MAYA

1989
Pt I

G. K. V.
HARDWAR

111153

2050
Anand
11-11-93

२५।१०।९१

111153

र्वाधिक बिकनेवाली समाचार पत्रिका

माया

१५ फरवरी, १९८९

मूल्य : ६.००

[illegible]
गु० कां० [illegible]

3/11/09

111153

बिहार का शिक्षा-माफिया

आत्मकथा

बेनजीर की शादी की कशमकश

MAYA
1989
Pt I

7 L.
Pt. I

क्या चीन-पाक से दोस्ती असंभव है ?

111153

चीन-पाक से समझौते के लिए :

राजीव झुकेंगे या झुकायेंगे ?

केहर सिंह : फैसले पर विवाद क्यों ?

सफदर हाशमी की हत्या : कला को सत्ता की चुनौती

महाकुंभ

क्या ६ फरवरी सही सलामत गुजर सकेगी ?

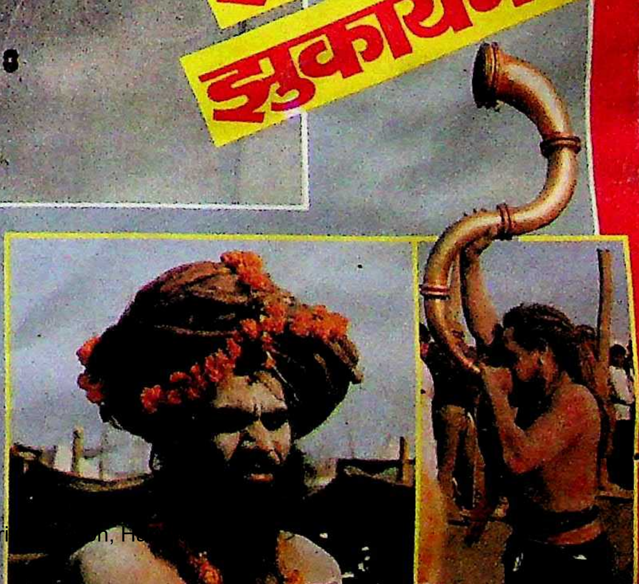

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri [illegible] H

माघ मकर गत रवि जब होई।
तीरथ पतिहि आव सब कोई॥
सकल काम प्रद तीरथराऊ।
बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ॥

महाकुम्भ पर्व १९८९ पर तीर्थराज प्रयाग में

बैंक ऑफ इंडिया

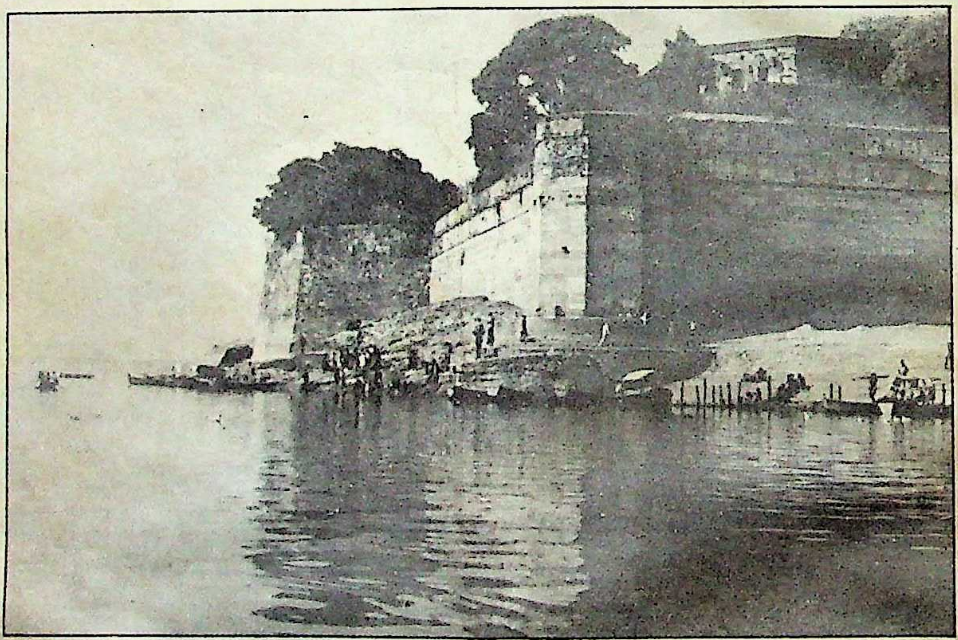

नेहरूजी ने कहा था...

"मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, यह लगाव बढ़ता रहा।
...कई बार मुझे याद आयी उस इतिहास की, उन परम्पराओं की, पौराणिक गाथाओं की, उन गीतों और कहानियों की जो कि कई युगों से उनके साथ जुड़ गयी हैं..."

उन्हीं परम्पराओं और गाथाओं को धरोहर के रूप में सहेजने और संवारने के लिए... नेहरूजी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए...अनवरत सेवारत बैंक

जवाहरलाल नेहरू जन्मशती
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

बैंक ऑफ़ इंडिया
BANK OF INDIA

बैंक आफ इंडिया
कुम्भ मेला नगर, हनुमान मार्ग

९ जनवरी से १५ मार्च तक आवश्यक बैंकिंग सेवाओं के साथ आपकी सेवा में सदैव तत्पर

(प्रधान कार्यालय : एक्सप्रेस टावर्स, नारीमन पाइंट, बंबई—४०००२१)

धूम मचा दे... रंग जमा दे.
PAN PARAG

PAN PARAG
पान पराग
स्वादिष्ट
सादे पान का मसाला
पान पराग
स्वादिष्ट
पान
पान पराग
स्वादिष्ट
पान
मसाला

आपका मनपसंद पान पराग,
डिब्बे और सुविधाजनक पाउच में.

अब स्वादिष्ट पान पराग जैसे चाहें वैसे लीजिए, डिब्बे या पॉकेट पाउच में... जहाँ जी चाहे ले जाइए — लुत्फ़ उठाइए. और पसंदीदा पान पराग के साथ ज़िंदगी की मौज-मस्ती का मज़ा लीजिए.

everest/d89/KP/15 hin

पान पराग®
पान मसाला

कोठारी उत्पादन

भारत का सब से अधिक बिकने वाला पान मसाला

DORA POCKET WALA

A Unique Inspiration !

जब आप सफर पर हों,
डोरा पॉकेट वाला
अण्डरवीयर
की अनिवार्यता से आप
चकित हो जायेंगे

◁ अदृश्य, गहरे
दो पॉकेटों
में रखिये वो चीज़
जिनको आप खो
नहीं सकते !

सुरक्षा का एक
अनोखा अनुभव

डोरा®
पॉकेट वाला अण्डरवीयर

एच.पी. टेक्सटाईल मिल्स कलकत्ता • नई दिल्ली • अहमदाबाद • कानपुर • बम्बई

Ankur/HPT/389

Dora
Dora
Dora
HPM
CALCUTTA INDIA

ंस्थापक
व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
धान संपादक
ालोक मित्र
युक्त संपादक
ाबू लाल शर्मा
प संपादक
नोद कुमार मिश्र
नेश दीनू
लोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
० मुश्ताक अली
रो प्रमुख
बई : रवीन्द्र श्रीवास्तव
खनऊ : अजय कुमार
रिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
ना कक्कड़
शेष संवाददाता
टना : विकास कुमार झा
वाददाता
खनऊ : सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
पाल : सुधीर सक्सेना
पुर : ओम सैनी
ला निदेशक
प्रकाश मुखर्जी

धान कार्यालय : २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ : ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स : ४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय : ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ स्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन : ३३१७४१६, ४७९३ टेलेक्स : ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय : बी-, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, नऊ-२२६००१, फोन : ३६२६२/३४४७७ पटना लय : ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन : २६७४०, ल कार्यालय : एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ : ६५९६८, बंबई कार्यालय : ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन बंबई-४०००२१, फोन : २४३५७७, तार : माया कहानी, स : ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय : स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता : २९१०३५

surcharge .50 paise per copy for rugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, hmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Blair, Tinsukia and Tezepur. For rtala, it is 25 paise.

©

स अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

Ankur/HPT/389

माया

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ६०, अंक ३ १५ फरवरी, १९८९

आवरण कथा

३०

राजीव गांधी की चीन और पाकिस्तान की यात्राओं के समय, उद्देश्य और नतीजों के संबंध में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण व्यक्त किये जा रहे हैं। आरोप है कि प्रधानमंत्री चुनावी लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि देकर चीन से दोस्ती की अतिउत्साही पहल कर रहे हैं। राजीव गांधी ने यात्राओं के दौरान विवादास्पद मुद्दों पर जो नीति अपनायी है, क्या वह वास्तव में घाटे का सौदा है?

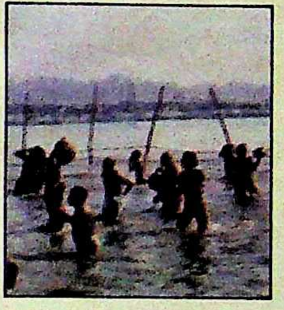

६६ महाकुंभ

वे कौन सी खामियां हैं जो ६ फरवरी (मौनी अमावस्या) के पर्व के लिए घातक बन सकती हैं?

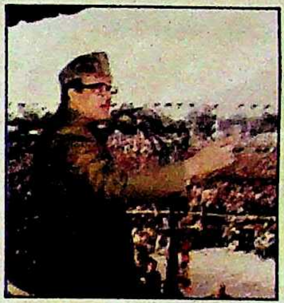

२० रैलियों की राजनीति

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आधार मजबूत कर रहे राजीव गांधी की रैली के जवाब में जनता दल की रैली-दर-रैली

७३ सफदर हाशमी

नुक्कड़ नाटकों के मेधावी कलाकार सफदर हाशमी के हत्यारों को क्या सरकार सजा देगी?

१७ केहर

केहर सिंह को फांसी देने का फैसला इतना विवादास्पद क्यों बना?

८१ बेनजीर

पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो कैसे अपनी मां की पसंद आसिफ जरदारी से शादी करने को राजी हुईं?

५३ शिक्षा माफिया

सहकारिता-माफिया से भी विकराल शिक्षा-माफिया से आजाद सरकार (बिहार) के टकराव का माजरा

देश : चुनाव सुधार विधेयक : सुधार का झंडा या सत्ता का हथकंडा? २३
प्रसंगवश : राजीव गांधी का तिब्बतियों के साथ विश्वासघात? ४३
उत्तर प्रदेश : स्थानीय निकाय चुनाव का जोर ४७
आंध्र प्रदेश : इंका विधायक की हत्या : क्या रामाराव का महल ढहेगा? ५०
मध्य प्रदेश : अर्जुन की मांद पर धावा ५२
राजस्थान : नारीशाला में क्या होता है? ५८
राजस्थान : जनता दल में अंतर्कलह ६१
महाराष्ट्र : शिवसेना का तृतीय अधिवेशन :
आम चुनाव जीतने का रिहर्सल ६३
दिल्ली : किसकी दिल्ली, किसकी शान? ६४
विदेश : निष्कासित शाह का संघर्ष ८०
खोजखबर : उप्र राज्य विद्युत परिषद में सेवानिवृत्तों की तूती ८६
फिल्म : केबिल टीवी का आतंक ९०
अर्थतंत्र : शेयर बाजार की असलियत ९६
खेल : नवजोत सिंह सिद्धू पर हत्या का आरोप! १००
खेल : सचिन तेंदुलकर : कम उम्र, पर लम्बी पारी १०१

आवरण पारदर्शी
मनमोहन शर्मा
(कुम)

maxell
TDK
तुलसी
ज़र्दा
00

सर्वश्रेष्ठ...
सर्वोत्तम...
सर्वप्रथम... ज़र्दा पाऊच में

तुलसी ज़र्दा

- सुविधाजनक आकार
- सुविधाजनक कीमत
- असली ताज़ा ज़र्दे का भरोसा... हर बार!

शानो शौकत के ढंग... तुलसी ज़र्दा के संग

अनेकानेक वैरायटीज़ में उपलब्ध
धर्मपाल सत्यपाल

श्रद्धांजलि

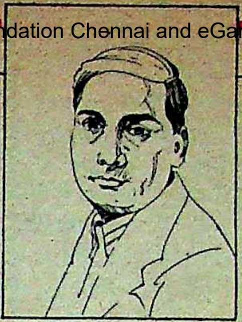

श्री क्षितींद्र मोहन मित्र

'माया बाबू' एक नाम नहीं, इतिहास है—हिंदी कथा साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता के विकास का। यों तो 'माया' के यशी संपादक का असली नाम श्री क्षितींद्र मोहन मित्र था, लेकिन 'माया' के साथ वे इतने एकाकार थे कि उनके अथक श्रम, अध्यवसाय और अप्रतिम संघर्षशीलता से जब 'माया' जनप्रिय हुई, तो वे भी जनप्रदत्त नाम 'माया बाबू' के रूप में लोकप्रिय हुए।

माया बाबू कितने मेधावी थे, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उनका जन्म २६ नवंबर, १६०८ में हुआ था और उन्होंने १६२६ में यानी २१ वर्ष की अवस्था में 'माया' के प्रकाशन-संपादन का चुनौतीपूर्ण कार्य अपने हाथ में ले लिया। वे अहिंदीभाषी थे, लेकिन हिंदी उनके लिए मात्र भाषा नहीं, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का ध्वज थी, जिसे वे 'माया' के रूप में प्रत्यक्ष योगदान देकर जन-जन के मन में फहराना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे क्रांतिकारियों की परोक्ष सहायता करके वे यूनियन जैक की जगह तिरंगे को लहराता देखने के लिए आतुर थे। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने १६ वर्ष की अवस्था में हिंदी सीखना आरंभ किया और मात्र पांच वर्ष के अंतराल के बाद उन्होंने 'माया' के संपादकीय दायित्व को संभालने के लिए अपने को सक्षम बना लिया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी शासन की कुनीतियों और निरंकुशता से जूझते हुए हिंदी कथा साहित्य और पत्रकारिता को जो गति, जो आयाम, जो दिशा दी, वह अपने आप में एक इतिहास है। विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कथाकृतियों को हिंदी पाठकों के सामने रखने का सर्वप्रथम कार्य कदाचित माया बाबू ने ही किया। पाठकीय रुचि, आवश्यकता एवं राष्ट्रहित उनकी संपादकीय नीति के तीन प्रमुख स्तंभ थे और इन्हीं पर स्थापित है 'माया' की अक्षत विश्वसनीयता की सर्वोच्च इमारत।

विश्वसनीयता का दावा नहीं किया जाता, वह अर्जित की जाती है और इसके लिए नया इतिहास रचना पड़ता है, एक नयी परंपरा का सृजन करना पड़ता है—और छह दशकों के इसी इतिहास, इसी परंपरा ने 'माया' को पहले कथा साहित्य के क्षेत्र में शीर्षस्थ होने और बाद में समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसारित होने का गौरव प्रदान किया है।

एक के बाद दूसरी चुनौती को आमंत्रित करना माया बाबू का दर्शन था और यही दर्शन उनके द्वारा स्थापित 'मित्र प्रकाशन' के निरंतर विकास और विस्तार का मूल प्रेरणास्रोत है। मनुष्य की काया चिरजीवी नहीं होती, लेकिन उसका दर्शन कालजयी होता है। यही कारण है कि ११ फरवरी, १६५७ को माया बाबू के भौतिक साहचर्य से वंचित हो जाने के बावजूद उनका दर्शन मित्र प्रकाशन का निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है। आज मित्र प्रकाशन देश का अग्रणी पत्रिका प्रतिष्ठान है जो 'माया', 'मनोरमा', 'मनोहर कहानियां', 'सत्यकथा', 'प्रोब इंडिया' (अंग्रेजी), 'आलोकपात' (बंगला), 'मनोरमा' (बंगला), जैसी लोकप्रिय और बहुप्रसारित पत्रिकाएं अत्याधुनिक तकनीक के जरिये प्रकाशित करके सुधी पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा है।

११ फरवरी, १६८६ को 'माया' के प्रातः स्मरणीय संस्थापक माया बाबू की ३२वीं पुण्य तिथि है। इस अवसर पर पत्रकारिता के इस शलाका पुरुष को 'माया' परिवार का शत् शत् प्रणाम!

चिट्ठियां

माया
कांग्रेस बनाम कांग्रेस
विपक्ष बनाम विपक्ष

कांग्रेस बनाम कांग्रेस, विपक्ष बनाम विपक्ष

३१ जनवरी का अंक मिला। सभी अंकों की तरह यह भी एक संग्रहणीय अंक था। आवरण कथा 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस, विपक्ष बनाम विपक्ष' अत्यधिक तथ्यपूर्ण तथा रोचक थी। यह सत्य है कि कांग्रेस में जो एक-दूसरे की टांगखिंचाई का महोत्सव चल रहा है, उसे राजीव की शह प्राप्त है। उन्हें पता है कि अगले चुनावों में उन्हें अंधा बहुमत नहीं मिलेगा, अतः वह किसी को इतना उठने देना नहीं चाहते कि स्वयं उनके लिए खतरा पैदा हो जाये। लेकिन विपक्षी नेता किस लिए एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, समझ में नहीं आता। वस्तुतः आज भारत का हरेक नेता चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्षी, निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। सभी के लिए 'अहं' प्रमुख है, देशहित 'गौण'। ऐसे में देश का क्या होगा? **—अनुराग पचौरी, भारतीय जनसंचार संस्थान, नयी दिल्ली**

हिंसा और सेक्स को समर्पित

'माया' (३१ जनवरी) में हिंदी सिनेमा का वर्ष १६८८ का समग्र विश्लेषण पढ़ा। यह लेख ऐसा था जिससे मैं पूर्णतः समहत हूं। वास्तव में इस वर्ष 'कयामत से कयामत तक' को छोड़कर प्रत्येक फिल्म हिंसा व सेक्स के फार्मूले पर आधारित थी। शायद आज निर्माता दर्शक को घिसे-पिटे फार्मूलों से भरी फिल्में दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। लेकिन इस वर्ष दर्शकों ने भी बता दिया कि वे इतने मूर्ख नहीं हैं। इस वर्ष केवल वे फिल्में ही स्वीकार की गयीं, जो लीक से हटकर थीं, वरना अच्छे कथानक वाली 'दयावान' क्यों पिटती? **—हर्ष कुमार, देवपुरम्, मुजफ्फरनगर, उप्र**

राजीव के लिए घातक या माफिक?

'माया' की १५ जनवरी की आवरण कथा 'मध्यावधि चुनाव: राजीव के लिए घातक या माफिक?' पढ़ी। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस प्रलोभन देकर, चुनाव सुधार तरीकों, रोजगार उपलब्ध कराने के आश्वासन देकर विपक्षी एकता को खंडित करने की जीतोड़ कोशिशें कर रही है। मगर इस बार विपक्षी एकता भी कमजोर नहीं है। अगर ऐसा संभव होता, तो १६७७ के चुनाव में कांग्रेस क्यों हारती?

मतदान की उम्र घटाकर १८ वर्ष करने से मतदाताओं की वृद्धि तो होगी ही। यदि नौजवान कांग्रेस के आश्वासनों से संतुष्ट हुए, तो उसकी डूबती नैया पार लग सकती है। **—प्रसन्न गंगराड़े, इटारसी, मप्र**

शेर-ए-बिहार—डा० जगन्नाथ मिश्र

१५ जनवरी, १६८६ की 'माया' में विशेष संवाददाता की विशेष रिपोर्ट 'कांग्रेस छोड़कर कहां जायेंगे जगन्नाथ?' पढ़ी। रिपोर्ट पढ़कर आश्चर्य हुआ कि डा० जगन्नाथ मिश्र जैसे लोकप्रिय नेता, अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के मसीहा, बलात्कार एवं नारी जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले बिहारवासियों के बेताज बादशाह के प्रति संवाददाता महोदय ऐसी गलत धारणा रखते हैं। डा० जगन्नाथ मिश्र के बिना बिहार में कांग्रेस-इ अनाथ हो जायेगी। बिहार में कांग्रेस-इ उसी समय तक जीवित है, जब तक कांग्रेस का झंडा डा० मिश्र के हाथ में है।

—डा० एसएम तैयब, सचिव, राष्ट्रीय जन जागरण समिति, मोतिहारी, बिहार

पंजाब: बरनाला का प्रायश्चित

'माया' (१५ जनवरी '८६) में प्रकाशित लेख 'पंजाब: बरनाला का प्रायश्चित' पढ़ा जो तथ्यों से पूर्ण है। इस संबंध में एक तथ्य यह भी है कि 'मैं पापी हूं और परमात्मा ही मुझे माफ कर सकता है।' बरनाला द्वारा माफी मांगे जाने और सजा को मंजूर करने पर देश भर में रोष की अनुगूंज सुनायी दे रही है। यह रोष न्यायसंगत ही है,

क्योंकि कट्टरतावाद और हठधर्मिता, उदारवाद और लोकतांत्रिक स्वभाव को कदापि नही सुहाते।

श्री बरनाला और मुख्यग्रंथियों ने जो कुछ किया है, वह धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए हाल ही में किये गये प्रयासों को एक चुनौती है। इससे कट्टरतावादियों के हौसले बुलद होते हैं और सिख भी भयभीत हुए हैं, जिन्होंने मुख्यग्रंथियों के व्यक्तिगत जीवन और सोच के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था। सिख समुदाय पुन: उसी उलझन में आ फंसा है जिसमें किसी भी ऐसे गुट के मनमाने आदेश का आंख बंद करके पालन करना पड़ता है, जिसका अकाल तख्त पर नियंत्रण हो। फिर चाहे वह नियंत्रण किसी भी हथकंडे से हुआ हो और कितनी ही अवधि के लिए हुआ हो। **—पीसी श्रीवास्तव, सिरसा, इलाहाबाद**

जनता दल: फिर दलदल में

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तुष्टीकरण की नीति अपना कर उन व्यक्तियों की भीड़ एकत्र कर ली है जिनकी जनता में कोई विश्वसनीयता नहीं है। जनता पार्टी वास्तव में केवल नेता पार्टी है, उसमें कोई जनता नहीं है। यदि वीपी सिंह केवल कार्यकर्ता आधारित एवं अनुशासित दल भाजपा का नेतृत्व करते, तो निश्चय ही सत्ता का विकल्प सभव हो जाता। सुब्रह्मण्यम स्वामी एवं शहाबुद्दीन जैसे संतों के रहते किसी भी पार्टी की लुटिया डूबना कोई आश्चर्य की बात नहीं।**—अजय मूंदड़ा, आनंद बाजार, मीलवाड़ा**

बेनजीर के जीवन की खौफनाक रात

'माया' का १५ जनवरी का 'बेनजीर के जीवन की वह खौफनाक रात' पढ़ा। वास्तव में विश्वासघाती जनरल जिया-उल-हक ने स्व० भुट्टो और उनके पूरे परिवार पर जो जुल्म ढाया, वह बेहद दर्दनाक व इंसानियत की मान्यताओं से हटकर था। विश्व के प्राय: सभी राष्ट्राध्यक्षों की भुट्टो को क्षमा करने की अपील पर उसने कत्तई ध्यान देना उचित नहीं समझा। यही वजह है कि जालिम जिया की कारगुजारियों को खुदा भी नहीं बर्दाश्त कर सका और बेकसूर भुट्टो की मौत का बदला उसे अपने आप ही मिल गया। यही नहीं, पाकिस्तान के सामान्य जन-जीवन में जहां आज उक्त तानाशाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है, वहीं स्व० भुट्टो की बेटी बेनजीर प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते ही अपने इस ऐलान से कि 'जिया के परिवार के साथ वे बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं करेंगी' पूरे विश्व में अपनी उदारता, सदाशयता व आदर्श का एक उत्कृष्ट नमूना बन गयी हैं।—**हीरालाल शर्मा, डोभी, जौनपुर, उप्र**

मधुलिमये की नयी रणनीति

मधुलिमये की नयी रणनीति को पढ़ने के लिए ही 'माया' खरीदा (१५ जनवरी, १९८९। ब्राह्मण जाति से आने वाले मधुलिमयेजी ने बचकानी बातों को ही दोहराया है कि विपक्ष को सभी जाति और धर्मों के लोगों को आकर्पित करना होगा। इसी बात को भारत की आम जनता विपक्षी दलों के नेताओं से करवाना चाहती है। इस बार संघ को छोड़कर सभी विपक्षी दलों को मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मात्र एक उम्मीदवार खड़ा करना होगा, लेकिन विपक्षी दल वाले बच्चे की तरह 'लालीपाप' के लिए डटे हैं। **—आशीश कुमार चौधरी, लहेरिया सराय, दरभंगा, बिहार**

विवाद: सोनिया के जन्म दिवस का

'माया' (१५ जनवरी, ८९) में रिपोर्ट 'विवाद: सोनिया के जन्म-दिवस का' बेहद सटीक एवं मनोरंजक लगी। आजकल राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन चापलूस राजनेताओं ने सत्ता में बने रहने के लिए चापलूसी के सारे कीर्तिमान तोड़ दिये हैं।

—मु० सगीर अहमद, खड़सारी, जमुई, बिहार

न्यू ईयर मनाऊं कैसे!

हिंदी में प्रकाशित 'धर्मयुग', 'रविवार', 'दिनमान' और 'माया' की समीक्षा करने पर 'माया' ही सर्वोत्कृष्ट दिखी। १५ जनवरी का अंक बेहद अच्छा लगा। दरबारी लाल द्वारा लिखित 'न्यू ईयर मनाऊ कैसे!' एकदम अनूठा था। यह व्यंग्यात्मक तो था ही, सजीव व चुटीला भी था। संपूर्ण पत्रिका के अंतर्गत 'दिल्ली दरबार' की व्यापक भूमिका रहती है। इतनी निष्पक्ष एवं बेबाक पत्रिका आज तक देखने को नहीं मिली। **—डा० रामकुमार बैरागी, जावरा, रतलाम, मप्र**

डा० जगन्नाथ मिश्र

राम जेठमलानी

राष्ट्रीय एकता इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके तरफदारों के सामने दो ही काम हैं—कांग्रेस-इ को सत्ता से हटाना और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना।**—बीटी रणदिवे (मार्क्सवादी नेता), त्रिवेंद्रम में**

मेरे पास इस बात के काफी सबूत हैं कि भागवत झा आजाद (बिहार के मुख्यमंत्री) अपने छात्र जीवन में दो बार रांची के पागलखाने में रह चुके हैं और उन्हें अब भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं।**—डा० जगन्नाथ मिश्र, पटना में**

जैनेंद्र की मृत्यु से प्रमाणित हो गया है कि इस (दिल्ली) जैसा निरक्षर और असभ्य शहर शायद ही कोई हो। **—प्रभाष जोशी, जनसत्ता में**

अब जनता दल के बारे में ही सोचना है, नेता दल के बारे में नहीं। **—देवीलाल, दिल्ली में**

दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में इतना ऊंचा कोई नहीं उठा, जितने राजीव गांधी और इतने ही थोड़े समय में कोई जनता की नजरों में इतना गिरा भी नहीं, जितने राजीव गांधी गिरे हैं।**—लालकृष्ण आडवाणी, दिल्ली में**

मैं आप (पत्रकारों) को यकीन दिलाता हूं कि (भारत का) मीडिया (प्रचार माध्यम) मेरा दुश्मन ज्यादा है, पाकिस्तान का कम।**—राजीव गांधी, इस्लामाबाद में**

यह अतिरंजना नहीं है कि लोग मुझमें एमजी रामचंद्रन को देखते हैं। **—जयललिता, मद्रास में**

भ्रष्टाचार के खिलाफ वीपी सिंह के तेवर महज दिखावा हैं, क्योंकि जनता दल में ऐसे कई बड़े पदाधिकारी हैं, जिनकी छवि साफ नहीं है। **—सुब्रह्मण्यम स्वामी, दिल्ली में**

सरकार ने (केहर सिंह के रूप में) एक बेकसूर आदमी को मार डाला है। इस बेइंसाफी के लिए गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय दोनों जिम्मेदार हैं, पर सबसे अधिक जिम्मेदार है, केंद्र सरकार।**—राम जेठमलानी, दिल्ली**

राजीव गांधी एक हीरे के समान हैं, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस हीरे को नष्ट न करें। **—कल्पनाथ राय, न्यूजट्रेक में**

अगर वे (कांग्रेस-इ) झटके-से चुनाव कराते हैं, तो हम (जनता दल) झटके-से विजय पा लेने को भी तैयार हैं।**—वीपी सिंह, बस्ती में**

कांग्रेस में इतना दम ही नहीं है कि बगैर कांशीराम से राय-मशविरा किये चुनाव के लिए कदम बढ़ाये। **—कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी के नेता**

कांग्रेस के लोग तो मुझे भ्रष्ट कहेंगे ही—झूठा हर किसी को झूठा कह सकते हैं।**—लालडेंगा, ऐजल में**

यह (राजनीति का संप्रदायीकरण) शुरू किया श्रीमती गांधी ने और उनके बेटे ने इसको व्यापक बना दिया।**—चंद्रशेखर, नयी दिल्ली में**

चोटी तक पहुंचने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस तरह पी जाती है और किस तरह धुत होने के बाद भी खड़ा रहा जाता है।**—यूरी चुबनिव (ब्रेझनेव के दामाद), 'मास्कोस्काया प्रावदा' में**

ऐसा लगने लगा है कि अमरीकी, सोवियत संघ की फिर से खोज कर रहे हैं और हम अमरीका की। **—मिखाइल गोर्बाचेव**

कुंभ मेला प्रशासन ने सरकार से करोड़ों रु० की भारी रकम प्राप्त की तीर्थयात्रियों के नाम पर, किंतु सारा धन अपनी स्वार्थ-पूर्ति में ही लगाया। **—स्वामी प्रमुदत्त ब्रह्मचारी, झूंसी में**

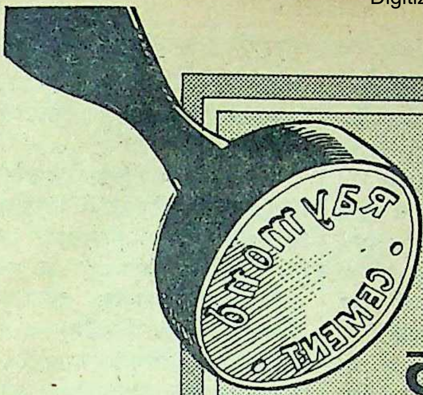

जब किसी निर्णय पर सालों-साल साथ निभाने की बात निर्भर हो तो ठोस प्रमाण उसमें मदद करते हैं

प्रमाण १ : गुणवत्ता
रेमण्ड का नाम ही सर्वोच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय है.

प्रमाण २ : मज़बूती
बी आइ एस के मानकों से निश्चय ही ज़्यादा 'कॉम्प्रेसिव' शक्ति.

प्रमाण ३ : ब्लेन
महीनतम ब्लेन के कारण अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मनचाही मज़बूती की गारंटी.

प्रमाण ४ : जमाव गुण
रेमण्ड सीमेंट पूर्ण जमाव का आश्वासन देता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव की अवधि बी आइ एस मानकों से बेहतर है.

प्रमाण ५ : विक्रेताओं का जाल
देशभर में रेमण्ड के अधिकृत विक्रेताओं का जाल शत प्रतिशत असली सीमेंट उपलब्ध कराता है.

प्रमाण ६ : पैकेजिंग
स्वचालित रोटरी पैकेजिंग मशीनों द्वारा सबसे मज़बूत प्लास्टिक और जूट की बोरियों में पैक याने निकाल लिए जाने का अंदेशा ही नहीं.

प्रमाण ७ : बचत
कोई अन्य सीमेंट हर बार इतने ठोस लाभों की गारंटी दे नहीं सकते.

प्रमाण ८ : हमारे कुछ ग्राहक
एन टी पी सी, ऑयल इंडिया लि., भारतीय रेलवेज़, वायजैक स्टील प्लांट, ईस्ट इंडिया होटल्स लि., आइ टी सी लिमिटेड, वोल्टास लि., टाटा रोबिन्स फ्रेसर, निटको टाइल्स, अंसल हाउसिंग प्रा. लि., एस.आर.एफ. निप्पॉन डेनरो इस्पात लि. जी.ई.सी.

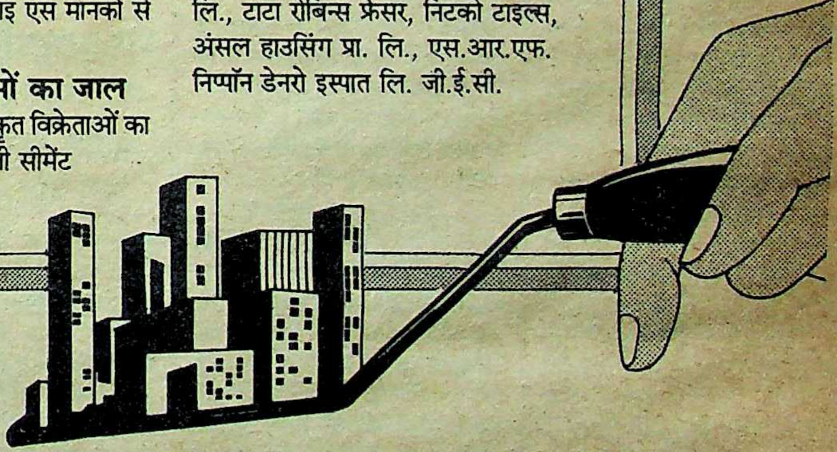

कैलाश सीमेंट : निर्माता

रेमण्ड

गुणवत्ता का दूसरा नाम.

कैसे पछाड़ा मुंशी ने देव को ?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संतोष मोहन देव ने वीपी सिंह के इलाहाबाद लोकसभा उप-चुनाव में उप्र के कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ काफी सख्त रिर्पोट पार्टी हाई कमान को देकर उनको नीचा दिखाने की जो कोशिश की थी, उसका बदला उप्र के नेताओं ने उनको (देव) पिछले दिसंबर महीने में बंबई में हुए अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ के चुनाव में बुरी तरह हरा कर ले लिया। उप्र की वजह से संतोष मोहन देव चुनाव हार गये और उनके कट्टर विरोधी केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री प्रिय रंजनदास मुंशी चुनाव जीत गये। संतोष मोहन देव इलाहाबाद लोकसभा उप-चुनाव में केंद्रीय प्रेक्षक थे।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मैदान में संतोष मोहन देव तथा प्रिय रंजनदास मुंशी में सीधी टक्कर हो रही थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जब यह बताया गया कि उनके दो मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सुझाव दिया कि महासंघ में जिसके पास ज्यादा समर्थन हो वही मैदान में रहे। चुनाव में देव और मुंशी का टकराव ठीक नहीं है। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जगदीश टाइटलर को यह काम सौंपा गया कि वे पता लगायें कि किसके पास अधिक ताकत है। टाइटलर ने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद यह रिपोर्ट दी कि संतोष मोहन देव की स्थिति मजबूत है, इसलिए प्रिय रंजनदास मुंशी को चुनाव मैदान से हट जाना चाहिये। मुंशी चुनाव मैदान से अपना नाम वापस लेने ही वाले थे कि उप्र के कुछ नेता उनसे मिले और उन्होंने कहा कि वह मैदान से न हटें, हम लोग उनको जितायेंगे। राजस्थान के रामनिवास मिर्धा, जो केंद्र में कपड़ा मंत्री भी हैं, भी मुंशी के पक्ष में उप्र की लाबी के समझाने-बुझाने पर आ गये। इसके बाद केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित भी मुंशी के पक्ष में सक्रिय हो गयीं। लेकिन संतोष मोहन देव को टाइटलर की रिपोर्ट पर पूरा भरोसा रहा और कई लोगों के कहने के बावजूद उन्होंने मैदान से हटने से साफ इनकार कर दिया।

जब बंबई में चुनाव हुए तो संतोष मोहन देव चुनाव हार गये। कहा जा रहा है कि प्रिय रंजनदास मुशी को प० बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटवाने में भी देव ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। मुंशी ने उसका बदला भी उनसे ले लिया।

बीस साल पुरानी किस्त का चक्कर

तमिलनाडु चुनाव में कांग्रेस हाई कमान ने दिल्ली से जो प्रेक्षक भेजे, उनको एक टेलीफोन डाइरेक्टरी तथा जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की लिस्ट दी गयी। प्रेक्षकों को कहा गया कि वे लोग अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंच कर कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं से संपर्क स्थापित करें और उन्हें निर्वाचन केंद्रों पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें। प्रतिनिधि बनाने के पहले उनको पूरी तरह समझायें कि मतदान के दिन उनको किस प्रकार काम करना होगा। पार्टी हाई कमान ने इसके लिए प्रेक्षकों को अलग से एक निर्देश पुस्तिका भी दी।

प्रेक्षक मद्रास जाने के बाद जिलों में चले गये। जब उन्होंने जिलों में जाकर पार्टी हाई कमान द्वारा बताये गये कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं से टेलीफोन पर या स्वयं जाकर संपर्क किया तो उनके हाथों से तोते उड़ गये। पार्टी हाई कमान ने प्रेक्षकों को कार्यकर्त्ताओं की जो लिस्ट दी थी, उसमें कुछ यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे और कुछ ने कांग्रेस कई साल पहले छोड़ दी थी। कुछ कार्यकर्त्ता अवश्य मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि वे लोग 'इंदिरा अम्मा' की कांग्रेस में थे, राजीव गांधी की कांग्रेस से उनका कुछ लेना-देना नहीं है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्त्ता अवश्य काम करने के लिए तैयार हो गये, लेकिन उन्होंने पारिश्रमिक [illegible] मांगा।

प्रेक्षकों ने तमिलनाडु पहुंच कर दिल्ली में कांग्रेस के २४ अकबर रोड स्थित मुख्यालय को फोन करके सारी स्थिति से अवगत कराया, तो उनको कहा गया कि वे लोग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीके मूपनार से संपर्क स्थापित करें। जब प्रेक्षकों ने मूपनार से संपर्क स्थापित किया, तो पता चला कि पार्टी हाई कमान ने तमिलनाडु के कार्यकर्त्ताओं की जो लिस्ट प्रेक्षकों को दी थी, वह बीस साल पुरानी थी। खैर, मूपनार ने उनको ताजा लिस्ट दी और बताया कि वे लोग इस लिस्ट के अनुसार काम करें।

पता चला है कि कांग्रेस हाई कमान ने तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक सख्त पत्र लिखकर इस बात की सफाई देने के लिए कहा है कि उनको समय पर कार्यकर्त्ताओं की नयी लिस्ट क्यों नहीं भेजी गयी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाई कमान को तुरंत एक छोटा-सा उत्तर भेज दिया था कि इस समय पूरी प्रदेश कमेटी चुनाव में लगी हुई है। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद उनको चुने गये विधायकों के साथ कार्यकर्त्ताओं की ताजा लिस्ट भेज दी जायेगी। पार्टी हाई कमान इस पत्र के पाने के बाद चुप बैठ गये।

वीर बहादुर पर अंकुश लगाने का नया दांव

उत्तर प्रदेश में वीरबहादुर सिंह पर लगाम लगाने के लिए नारायणदत्त तिवारी समर्थकों ने एक जोरदार दांव मारा है। दिल्ली दरबार ने जब से वीरबहादुर सिंह को अमेठी संसदीय क्षेत्र का कामकाज देखने की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से नारायणदत्त तिवारी समर्थकों को चैन नहीं मिल रहा है। स्वयं तिवारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी जिलों के दौरे तो किये, लेकिन अमेठी संसदीय क्षेत्र में वे झांकने तक नहीं गये (नवंबर १९८८ में प्रधानमंत्री के दौरे के समय को छोड़कर)। इस बारे में नारायणदत्त तिवारी कहते हैं, "अमेठी का कामकाज देखने के लिए जब वीरबहादुर सिंह और कैप्टन सतीश शर्मा मौजूद हैं, तब मैं अनावश्यक रूप से वहां के कामों में अड़ंगेबाजी क्यों करूं ?"

लेकिन इधर तिवारी समर्थकों ने वीरबहादुर के विरुद्ध जो दांव फेंका है, वह अपने आप में निराला है। इस दांव के तहत गोरखपुर के एक शक्तिशाली विधायक हरिशंकर तिवारी को इंका में शामिल कराने की मुहिम है। हरिशंकर तिवारी को वीरबहादुर का कट्टर विरोधी माना जाता है। दरअसल हरिशंकर तिवारी इन दिनों नारायणदत्त तिवारी के काफी नजदीक आ गये हैं। पिछले दिनों जब राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में क्रमशः वीरबहादुर और नारायणदत्त तिवारी खड़े हुए थे, तो तिवारी को वीरबहादुर से एक वोट अधिक मिला था। जानकार लोग बताते हैं कि यह वोट हरिशंकर तिवारी का ही था।

हाल ही में नारायणदत्त तिवारी ने हरिशंकर तिवारी से आधे घंटे तक एकांत में बात की और इसी के बाद से यह समझा जाने लगा है कि हरिशंकर तिवारी जल्द ही कांग्रेस में आ जायेंगे।

वैसे भी उत्तर प्रदेश इंका ने इन दिनों यह मुहिम चला दी है कि राज्य में जहां भी जो ताकतवर व्यक्ति हो उसे जैसे-तैसे कांग्रेस में लाया जाये, ताकि अगले चुनावों में साम, दाम, दंड, भेद से जीत हासिल की जा सके। इसी मुहिम के तहत पिछले दिनों प्रदेश इंका अध्यक्ष बलराम सिंह यादव ने बाराबंकी के आतंकवादी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये जा चुके रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को एक भव्य समारोह में इंका की सदस्यता ग्रहण करायी। यही नहीं, लखनऊ के एक बहुचर्चित सरगना अरुणशंकर शुक्ल उर्फ 'अन्ना', जिसे कुछ समय पूर्व लोकदल नेता मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया था, को इंका में लाने के लिए सूचना राज्यमंत्री नरेशचन्द्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में 'अन्ना' के घर में आयोजित एक पारिवारिक समारोह में राज्यमंत्री नरेशचंद्र ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 'अन्ना' ने नरेशचन्द्र को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इंका में शामिल हो जायेगा।

एक पत्ता तूफान में

बीड़ी बनाने के काम आने वाले तेंदू पत्ते को इकट्ठा करने में हर साल दस लाख से ज्यादा लोग जुटते हैं। इनमें से ज्यादातर आदिवासी होते हैं।

पीढ़ियों से इस काम पर कब्जा रहा है ठेकेदारों का।

अव इस धंधे से विचौलियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। तेंदू पत्ता मजदूर अब खुद अपनी मेहनत के मालिक होंगे क्योंकि वे सब सहकारी समितियों के सदस्य हैं।

जिनके स्वार्थ इससे जुड़े हैं उन्हें जाहिर तौर पर यह बदलाव रास नहीं आ रहा और उन्होंने तूफान सरीखा ही खड़ा कर दिया है- विवाद का।

क्या पत्ता सचमुच तूफान में है ?
या पत्ते का तूफान है यह ?
या फिर आदिवासियों का उठ खड़े होना उन्हें नागवार है?

म.प्र.माध्यम/तेंदू/503/88

हाथी-घोड़ा पालकी, जय बहुगुणा लाल की

तमिलनाडु चुनाव के बाद जब दिल्ली दरबार लुंगी और अंग वस्त्रम को उतार कर जींस वस्त्रम धारण करके वेस्टर्न म्यूजिक पर हौले से थिरकने को हुए, तो पीछे से दरबारियों ने उन्हें (घेर) ओढ़ लिया, "सर मन बहुत मचल रहा होगा। लेकिन इस मन पर चले, तो सिर पर लटक रहा सवा मन (वीपी सिह) टूट पड़ेगा। हुजूर, अगर जींस वस्त्रम का मोह बहुत सता रहा-हो, तो कम-से-कम उसके ऊपर ही यह खादी का लबादा (कुर्ता-पायजामा) लाद लें।" दरबार ने अपने शरीर की थिरकन को थोड़ा मंद करते हुए इशारे से पूछा, "आखिर, मैं एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा...कब तक लबादे के ऊपर लबादा लादता रहूंगा। इससे तो अब चुहिया (तमिलनाडु चुनाव) तक नहीं मर रही है।" दरबारियों को पीछे धकियाते हुए सीताराम केसरी आगे आ गये, "सर, हम राजनीतिज्ञों की लबादा ही नियति है। मरने को तो इस लबादे से हाथी (पिछला लोकसभा चुनाव) भी मर जाता है, न मरे तो पतंगा (यूपी के स्थानीय निकायों के चुनाव) भी नहीं मरता है। सब कुछ लबादे की हवा पर निर्भर करता है। लेकिन लबादा लादे रहना ही हमारी नियति है।"

दरबार ने नियति के आगे अपने मन को मय वेस्टर्न म्यूजिक के मरोड़ दिया और जींस वस्त्रम के ऊपर खादी वस्त्रम को ओढ़ लिया, तो खुशी से दरबारियों ने उछल-उछल कर तालियां बजाना शुरू कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट जब दरबार के साउंड ऐडवाइजर से पूरी तरह खिंच गयी, तो सिर मुंडाये, हाथ में टेलीफोन का चोंगा लिये गोरखपुर नरेश वीरू उस्ताद (वीर बहादुर सिह) गंभीर मुद्रा में अवतरित हो गये। वे चुप थे। दरबार ने आगे बढ़कर सांत्वना के स्वर में वीरू उस्ताद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि पत्नी का बिछड़ जाना काफी दुखदायी होता है! वीरू उस्ताद चुप रहे। दरबार फिर बोले, "मुझे लगता है कि आपको इस हादसे से काफी बड़ा सदमा लगा है।" अब वीरू उस्ताद से न रहा गया, "सर, पत्नी का जाना तो मेरा निजी दुख है। वीरू उस्ताद निजी दुख और सुख से ऊपर है।" दरबारियों ने तालियां पीट दीं, तो वीरू उस्ताद की गर्व से छाती फट गयी और बोले, "सार्वजनिक दुख और सुख ही मेरा जीवन है। यह नयी दिल्ली तिवारी का आपने कमाल देखा। स्थानीय निकायों के चुनाव में आपका पूरा भट्टा बिठा दिया। जब गुलाम भाई (गुलाम नबी आजद) ने उसे कसा, तो भागा-भागा वृंदावन गया और देवरहा बाबा से आशीर्वाद ले आया। अब तो आप उसे हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके सिर पर देवरहा बाबा ने अपना एक पैर रख दिया है।" दरबार वीरू उस्ताद की चिंता में डूबें कि उसके पहले गुलाम नबी आजाद ने उनको थाम लिया, "सर, वैसे तो नयी दिल्ली तिवारी ने सब चौपट कर दिया है, लेकिन मैंने नगरपालिकाओं के चुनाव में जीते निर्दलीय उम्मीदवारों की पीठ पर अपना पंजा (इंका का चुनाव चिह्न) गड़ा दिया है। काफी निर्दलीयों को ले-देकर अपने हाथ में कर लिया है।" दरबार के चेहरे पर संतोष का विस्फोट ह कि उसके पहले वीरू उस्ताद ने गुलाम नबी को पीछे धकिया दिया, "सर, यह नयी दिल्ली तिवारी की गहरी चाल है। हमने कहा था कि हवा उल्टी बह रही है, चुनाव न कराओ। लेकिन वह नहीं माना।" सीताराम केसरी ने पीछे से (धीमे स्वर में) हस्तक्षेप किया, "वीरू उस्तादजी चुनावों का ऐलान तो आप ही कर आये थे। तिवारीजी ने तो बस आपके ऐलान को कार्यान्वित कर दिया। इसमें महाराज का क्या दोष। आप जो बो आये थे उत्तर प्रदेश में, उसे तिवारी ने काट कर दरबार के सामने डाल दिया।" वीरू उस्तांद भड़क उठे, "मैंने जो बोय था, अगर मैं ही उसे काटता, तो आप देखते। नयी दिल्ली तिवारी ने हम लोगों को जड़-मूल से काटकर फेंक दिया है। अब हम लोगों को नये सिरे से अपनी फसल बोनी पड़ेगी।" केसरीजी आगे लपक कर कुछ बोलें कि उसके पहले ही दरबार ने प्रश्न कर दिया, "आखिर १७ साल से हम लोग स्थानीय निकायों के चुनाव रोके हुए थे। और कितना रोके रहते? मुझे तिवारीजी ने बताया था कि प्रदेश की राजनीतिक प्रक्रिया को अगर और रोके रखा गया, तो फिर हिंसा फैल सकती है। वैसे मैं हिंसा से डरता नहीं हूं। लेकिन हमारे अर्धसैनिक दस्ते पंजाब तथा दीगर जगह उलझे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे पास भेजने को कुछ नहीं था। इसीलिए मैंने कह दिया कि चुनाव ही करा लो।" वीरू उस्ताद से न रहा गया और वे तेजी से टप से बीच में आ गिरे,

वीरू उस्ताद, तिवारीजी के खिलाफ अपना गला फाड़े दे रहे थे कि इसी बीच गोपी अरोड़ा ने दिल्ली दरबार को 'हाथी-घोड़ा पालकी, जय बहुगुणा लाल की' ताजा फिल्म का वीडियो कैसेट पकड़ा दिया, "सर, मैं आपसे कहता था कि बहुगुणा अपोजीशन की राजनीति में तीसरा कोण बनायेंगे। देखिए—'हाथी-घोड़ा पालकी, जय बहुगुणा लाल की'। जार्ज ने गोपी अरोड़ा से कैसेट लेकर तुरंत उसे वीसीआर में डाला, तो दरबार ने आहिस्ता से पूछा, "लेकिन बहुगुणाजी का यह खेल कितने दिनों चलेगा?"

दिल्ली दरबार

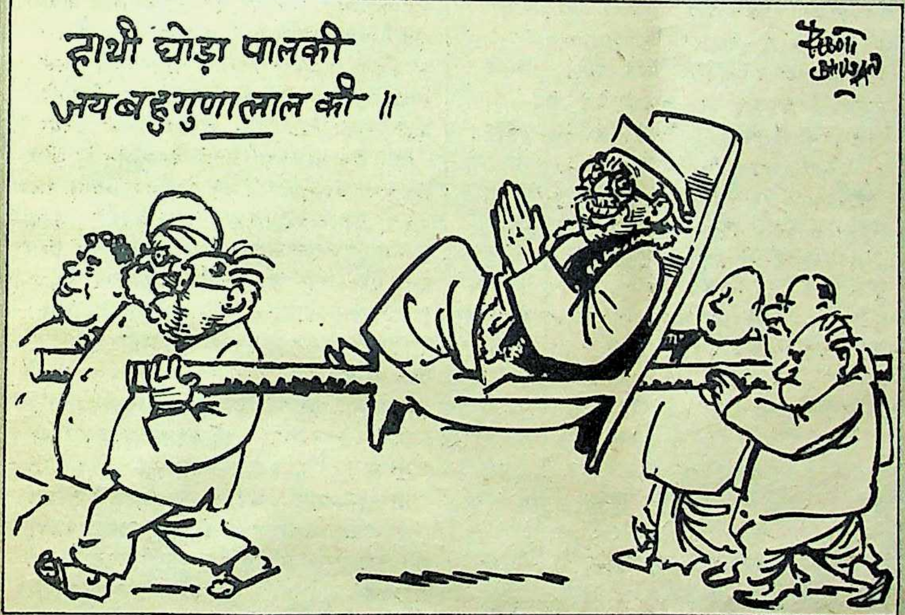

"सर, उसने आपको बहका दिया। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति तो मैं अपने 'अंडर वर्ल्ड' के हवाले करके दिल्ली आया था। उत्तर प्रदेश में हमारे गोरखपुरिये शाही-तिवारी के बिना पूछे राजनीति का पत्ता भी नहीं हिलता था। इस नयी दिल्ली तिवारी ने इन गोरखपुरियों के वरद हस्त पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। जनसंघियों (भारतीय जनता पार्टी) से इसकी पुरानी साठगांठ रही है। उनको लाने के लिए यह हमेशा उतावला रहता है। हुजूर, यह खादी के पायजामे के नीचे खाकी निकर हमेशा पहने रहता है। अब तो उसने हमारे यादव (बलराम सिंह यादव) को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन बलराम को नहीं मालूम कि तिवारी उसे ऐसी जगह मारेगा, जहां उसे पानी नहीं मिलेगा।" वीरू उस्ताद पंचम में इतना बोले कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा। लेकिन दरबारियों पर वीरू उस्ताद के प्रलाप से जूं तक नहीं रेंगी। इतने में गोपी अरोड़ा आकर दरबार के कान में फुसफसाये। उनके पीछे केदार नाथ सिंह सफदर हाशमी की हत्या से सहमे खड़े थे।

वीरू उस्ताद, तिवारीजी के खिलाफ अपना गला फाड़े दे रहे थे कि इसी बीच गोपी अरोड़ा ने दिल्ली दरबार को 'हाथी-घोड़ा पालकी, जय बहुगुणा लाल की' ताजा फिल्म का वीडियो कैसेट पकड़ा दिया, "सर, मैं आपसे कहता था कि बहुगुणा अपोजीशन की राजनीति में तीसरा कोण बनायेंगे। देखिए 'हाथी-घोड़ा पालकी, जय बहुगुणा लाल की'। जार्ज ने गोपी अरोड़ा से कैसेट लेकर तुरंत उसे वीसीआर में डाला, तो दरबार ने आहिस्ता से पूछा, "लेकिन बहुगुणाजी का यह खेल कितने दिनों चलेगा?" गोपी अरोड़ा ने अपने लंबे बाल संवारते हुए कहा, "सर, यह खेल जब तक आप चलायेंगे, तब तक चलेगा। यह मामला इंटरनेशनल है। जब तक आप गोर्बाचेव पर दबाव बनाये रखेंगे, तब तक केजीबी उन लोगों को तीन टांग पर नचायेगी।" दरबार ने बीच में बात काट दी, "वे ज्योति बाबू चुप नहीं बैठेंगे। वे खुलकर राजा मांडा के साथ आ जायेंगे, तो फिर क्या होगा?" गोपी अरोड़ा ने अपने बाल खुजलाते हुए कहा, "सर, ईएमएस और सुरजीत को तो लगा रखा है कि वे ज्योति बाबू की टांग खींचते रहें। अगर आप ऊपर (गोर्बाचेव) से थोड़ा सा दबाव डलवा दें, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। सारे मार्क्सवादी आपस में महाभारत के योद्धाओं की तरह लड़ मरेंगे।" दरबार की समझ में नहीं आया, तो उन्होंने गोपी अरोड़ा को करीब बुलाकर आहिस्ता से पूछा, "गोपीजी, इस खेल का कोई मतलब है?" गोपी अरोड़ा ने थोड़ा-सा मुस्करा कर उनके कान में कहा, "सर, मुझे नहीं लगता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कोई तीर मार लेंगे। अगर आपके तीर का तुक्का ठीक न लगा, तो इस वामपंथी तीसरे कोण यानी 'हाथी-घोड़ा पालकी, जय बहुगुणा लाल की' मदद से आप फिर से गद्दीनशीं हो सकते हैं। सर, इसीलिए मैंने दूरदर्शन पर बहुगुणाजी की पालकी का जुलूस काफी धूमधान से निकलवाया।" गोपी अरोड़ा अपना वाक्य भी पूरा कर नहीं पाये थे कि पीछे से एचकेएल भगत फट पड़े, "सरकार, गोपी अरोड़ा तो खामख्वाह इसका 'क्रेडिट' ले रहे हैं। बहुगुणाजी की सवारी धूमधाम से दूरदर्शन पर मेरे आदेश से निकाली गयी।" दरबार ने भगतजी को नजरअंदाज करते हुए आगे पूछा, "बहुगुणाजी का वामपंथी विचार अभियान भी हमारा ही कबाड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके प्रोग्राम काफी रेडिकल होंगे।" गोपी अरोड़ा ने फिर बात काट दी, "सर, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पायेंगे, क्योंकि आपका जो बिगड़ना था, वह बिगड़ चुका। अब जो कुछ बिगड़ेगा, वह वीपी सिंह, देवीलाल और एनटीआर का ही बिगड़ेगा। आपका बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है!" दरबार ने ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचने की मुद्रा में कहा, "अच्छा तो ऐसा है! फिर तो ठीक ही है। तो अब उनकी (विपक्ष) कमजोरी ही हमारी मजबूती है।" गोपी अरोड़ा ने दरबार को ढाड़स बंधाते हुए कहा, "नहीं सर, बिलकुल वैसा नहीं, जैसा अभी आपके भेजे में उतर गया। राजनीति एक ऐसे दौर में पहुंच गयी है कि आपकी कमजोरी, उनकी (विपक्ष) मजबूती है और उनकी (विपक्ष) कमजोरी आपकी मजबूती है।" दरबार धीमे से राजनीति का गोपी-दर्शन अपने अंदर उतारें कि उसके पहले ही कैप्टन सतीश शर्मा उनके कान में फुसफुसाये, "यार उस अपने सुब्रह्मण्यम स्वामी ने तो हेगड़े के गले में घंटी बांध दी है। बंगलौर का जमीन घोटाला अब हेगड़े से न निगलते बन रहा है और न उगलते। कमाल का आदमी है अपना वह स्वामी। अगर हम लोगों के साथ आ जाये, तो फिर...।" पास खड़े केसरीजी के कान में जब स्वामी...स्वामी गया, तो वे बोल पड़े, "अरे कप्तान साहब, वह नकली स्वामी है। असली स्वामी तो चंद्रास्वामी हैं। लेना हो, तो असली स्वामी को लो। वे साथ आ जायें, तो फिर हम लोगों के पौ बारह हो जायेंगे।" कैप्टन सतीश शर्मा ने पीछे घूमकर केसरीजी को घूर कर देखा, "केसरीजी आप अपनी नारदगिरी से बाज नहीं आयेंगे। जहां माल-पानी की बात आती है, आप अपना मुंह मार देते हैं। माना आप पार्टी के खजांची हैं, लेकिन हर जगह अपनी वह खजांचीगिरी क्यों दिखाते रहते हैं।" कैप्टन सतीश शर्मा बुरी तरह केसरीजी से उलझ गये, तो मौका पाकर वीरू उस्ताद दरबार के कान की तरफ लपके, "हुजूर, आप बाहर (विपक्ष) की कमजोरी में अपनी मजबूती ढूंढ़ रहे हैं। लेकिन वह नयी दिल्ली तिवारी आप की कमजोरी में अपनी मजबूती ढूंढ़ रहा है। बाहर (विपक्ष) से जब तक आप मजबूत होंगे, उसके पहले ही वह (नारायण दत्त तिवारी) आपको घर (पार्टी) के अंदर कमजोर कर देगा।" दरबार वीरू उस्ताद की बात भेजे में उतार कर मनन करें कि उसके पहले जार्ज ने वीसीआर पर काफी देरी से फंसे कैसेट को चला दिया, "बहुगुणाजी सात घोड़ों के रथ पर बैठे, अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, पीछे भीड़ में ईएमएस, सुरजीत, उन्नीकृष्णन, रामधन आदि-अनादि नारे लगा रहे थे—"हाथी-घोड़ा पालकी, जय बहुगुणा लाल की।"

—दरबारी लाल

कुंभ और नारी

सत्या मासी कुंभ पर आयीं, बिस्तरबंद, चमड़े का बड़ा थैला और कनस्तर थामे। स्टेशन पर रिक्शेवाले ने मांगे चार रुपए। उन्होंने घर पहुंच कर दे दिए पांच रुपए। तीरथ पर आयी हैं, पुण्य कमा कर जायेंगी। किसी का दिल दुखी न कर दें। रिक्शेवाला इतनी ठंड में चौक तक खींच कर लाया है। उनके लिए कमरे का एक कोना ठीक किया, तो बोलीं, "रहने दे, मैं घंटे दो घंटे में चली जाऊंगी। स्वामीजी का कंप लगा है काली सड़क पर, वहीं रहूंगी।"

"थोड़े दिन घर में रह लो। वहां ठंड है, बारिश भी हो सकती है।"

"तीरथ करने निकली हूं, ठंड-गरमी से नहीं डरती, जाकर अपनी कुटिया में टिकूंगी।"

"तंबू टपकेगा?"

"तो, मैं क्या अकेली हूं, मेरे जैसे हजारों-लाखों होंगी वहां।"

"अच्छा यह बताओ मासीजी, आप तीरथ करने क्यों निकली हैं?"

"ये सुनो, मैं क्या पहेली बार निकली हूं। सारे तीरथ कर डाले मैंने। हरिद्वार, ऋषिकेश, बदरीनाथ, केदारनाथ पुष्करजी, नासिक, उज्जैन, काशी, कहां तक गिनाऊ। बस प्रयाग का कुंभ रह गया था, वह भी पूरा हो जायेगा अबकी।"

"इतने तीर्थ आप क्यों करती हैं?"

"पाप जो धोने हुए।"

"कौन-कौन से पाप किये हैं आपने?"

सत्या मासी हंस पड़ीं—एकदम स्वच्छ दांतोवाली, भोली-भाली मुखाकृति की सरल, निष्पाप हंसी। बीसियों बरस से मैं इन्हें जानती हूं, जगतमासी हैं ये। हर एक के दुख में कातर, हर एक के सुख में शामिल। न किसी से बैर न द्वेष, पड़ोस में सबसे बोलचाल, रिश्तेदारों में मिलनसार, परिवार में आदरणीय, यहां तक कि बहुएं भी कभी इनकी आलोचना नहीं करतीं। वे सत्यामासी कुंभ के पर्व पर अपने कौन से पाप धोने आयी हैं, यह मेरी समझ से परे था।

सत्या मासी जब निरुत्तर होने लगती हैं, तो स्वामीजी की भाषा में बोलने लगती हैं, "पाप सिर्फ वह नहीं जो जान कर किया जाये, अनजाने भी पाप हो जाता है, उसी को धोने। अगर अपने पांव से एक चींटी भी मरी है, तो पाप के भागी हुए हम।"

अनजान पाप में उनके स्वामीजी के अनुसार बहुत से गांधीवादी निषेध हैं, जिनका अतिक्रमण पाप की कोटि में आता है। यहां तक कि जिस भी बात से शरीर सुख, आराम और गरमी पाये वह भी पाप है। पुण्य कमाने में कष्ट उठाना, उनका दिया मूलमंत्र है।

मैंने कहा, "मासीजी, आपसे भी तो लोग जाने-अनजाने में कभी बुरा बोले होंगे। जिस तरह जीरो से जीरो कट जाता है, पाप से पाप नहीं कट सकता क्या?"

"नहीं, पाप से पाप और मैल से मैल कभी नहीं कटता। पाप की काट पुण्य है, जिस तरह मैल की काट साबुन है।"

"मल मल धोऊं दाग नहि छूटत' जैसे भजन के बारे में आपकी क्या राय है?"

"तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूर नसावन।"

उनकी बडी बहन विद्यावती ने कहा।

मैं सोचने लगी हर तीर्थाटन में स्त्रियों की संख्या आखिर पुरुषों से इतनी अधिक क्यों होती है? क्या पुरुष पाप नहीं करते या उन्हें पाप धोने के लिए गंगा स्नान करना जरूरी नहीं है? स्त्रियों के मन में पाप और पुण्य की परिकल्पना इतनी जोर से बैठा दी गयी है कि वे मान कर चलती हैं कि उन्हें अपने शुद्धिकरण का काम जरूर करना है। इसीलिए वे शारीरिक श्रम, व्रत, उपवास और आराधना के कठिन कठोर क्रम में अपने जीवन की सार्थकता ढूंढ़ती हैं। स्त्री का मानवीय रूप पाप की अवधारणा से लिप्त समझा जाता है। सिर्फ देवी रूप में स्त्री पाप से परे और ऊपर है। मानवीय रूप में पग-पग पर उसके साथ पाप की आशंका बंधी है। कहीं वह पाप की कर्ता है, कहीं भोक्ता। कहीं पाप उससे हुआ है, कहीं पाप उसके प्रति हुआ है। दोनों ही स्थितियों में वह अपने को कलंकित और दोषी समझती है। अपने पाप-बोध से छुटकारा पाने के लिए वह तीर्थ करने निकलती है।

दोनों बहनें अपने दुखते घुटने, कांपते टखने और कंबल स्वेटर लेकर निकल गयीं स्वामीजी के आश्रम की तरफ।

ऐसा नहीं कि मेले में पुरुष हैं ही नहीं। पुरुष भी हैं, पर थोड़े। जो हैं, उनमें स्त्रियों की तरह कष्ट उठाने की संकल्पबद्धता नहीं है। अधिकांश एक दो प्रमुख स्नान-दिनों का लाभ उठाकर, पुण्य कमा कर वापस लौट जायेंगे। उनका विचार है 'कौन मरे ठंड में, जितना हो सका, बहुत है।' उन्हें पूर्ण विश्वास है कि संगम पर एक दो डुबकी लगाने से उनके समस्त पाप धुल गये और अब वे एकदम निष्कलंक हैं। यह आत्मविश्वास और आत्मकेंद्रितता स्त्री-भक्तों में नदारद है। वे मानती हैं कि उन्हें जीवनभर तपस्या करनी होगी, तभी उनकी चुनरी का दाग छूंटेगा।

पाप जब होता है, वह देह के साथ-साथ दिमाग और दिल पर भी असर डालता है। स्नान से सिर्फ देह का शुद्धिकरण होता है, बाकी दिल-दिमाग की शुद्धि के क्या मार्ग हैं, यह स्पष्ट नहीं है। फिर पाप और पुण्य दोनों अशरीरी अवधारणाएं हैं जिनका ताल्लुक धर्म से ज्यादा मनोविज्ञान से होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में ज्यादातर साधुओं के विचार निहायत घिसे-पिटे और अस्पष्ट मिले। सभी ने कहा, दिल दिमाग की शुद्धि कल्पवास से होती है, उनका प्रवचन सुनने से होती हैं, भजन-कीर्तन से होती है। तीन में से दो कार्यक्रमों में शामिल हो लेने के बाद भी मेरा दिमाग अपने सवालों से ज्यों-का-त्यों भरा हुआ था। स्वामी तिलकानंद ने प्रचंड क्रोध से कहा, "जब भक्तिभाव नहीं है, तो यहां क्या करने आती हो?" मुझे लगा मैं उनके व्यापार में बाधा बन रही थी। आखिर संसार की सबसे अमूर्त चीज का व्यापार इतना आसान नहीं होता। उसके लिए जो वाक्-चातुरी और मनो-माधुरी चाहिए, वह प्रश्नकर्ता नहीं वरन् मूक भक्तों की भीड़ की अपेक्षा रखती है। साधुओं ने नये वस्त्र सिलाये हैं भगवे कुर्ते, भगवे अंगरखे, भगवा चादर, भगवे जूते। समृद्ध साधुओं की रजाइयां भी भगवा रंग की हैं, चमकदार कीमती साटन या टेरिकाट की। रोज भव्य जुलूसों के साथ भिन्न-भिन्न अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं। इनकी सजावट शादी-ब्याह की बारात से ज्यादा है। जिन रथों पर वे सवार हैं, वे दूल्हें की कार से भी ज्यादा सजे हुए हैं। स्त्रियां धीमे-धीमे चंवर डुला रही हैं। पर क्या करूं मेरी नजर बार-बार उन दुर्बल, साधारण आदमियों पर उठती है जो इन रथों को बांध की चढ़ाई पर, अपने परिश्रम से खींच रहे हैं बिलकुल ऐसे जैसे मिस्र के सम्राटों का रथ गुलामों द्वारा खींचा जाता था।

—ममता कालिय

स्त्रियों के मन में पाप और पुण्य की परिकल्पना इतनी जोर से बैठा दी गयी कि वे मान कर चलती हैं कि उन्हें अपने शुद्धिकरण का काम जरूर करना है। इसीलिए वे शारीरिक श्रम, व्रत, उपवास और आराधना के कठिन कठोर क्रम में अपने जीवन की सार्थकता ढूंढ़ती हैं। स्त्री का मानवीय रूप पाप की अवधारणा से लिप्त समझा जाता है। सिर्फ देवी रूप में स्त्री पाप से परे और ऊपर है।

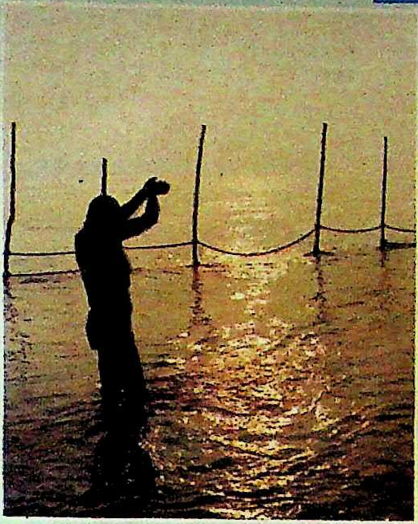

सूर्योपासना में लीन साधु

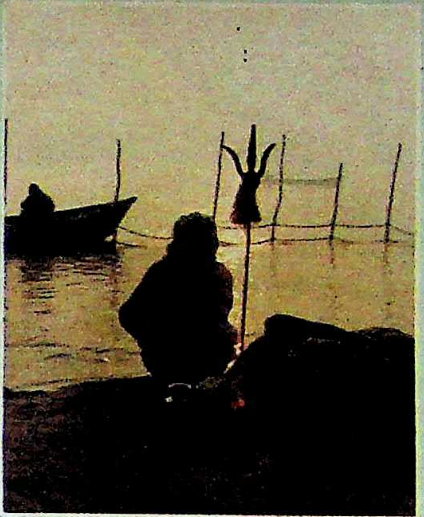

साधनारत संत

कुंभ मेले के प्रारंभिक पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर देश-विदेश के कोने-कोने से आये साधु-महात्माओं, धर्माचार्यों और तीर्थयात्रियों ने सश्रद्धा संगम में स्नान किया। आतंकवाद की आशंका, भगदड़ में लाखों लोगों के कुचले जाने की बीबीसी की कथित भविष्यवाणी की खबर, कड़ाके की ठंड और मार्गबाधा की वजह से रेलगाड़ियां विलंब से पहुंचने के कारण भीड़ अपेक्षा से कम रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ४० लाख लोगों ने संगम में स्नान किया, जबकि गैरसरकारी अनुमान १०-१२ लाख तीर्थयात्रियों के पहुंचने का है। मेला चरमोत्कर्ष पर मौनी अमावस्या (६ फरवरी) के दिन पहुंचेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि उस दिन लगभग डेढ़ करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे और उस दिन इलाहाबाद संसार का सर्वाधिक आबादीवाला नगर हो जायेगा। यद्यपि मकर संक्रांति तक पूरी तैयारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो स्थिति है, उससे यह नहीं लगता

छाया : मनमोहन शर्मा

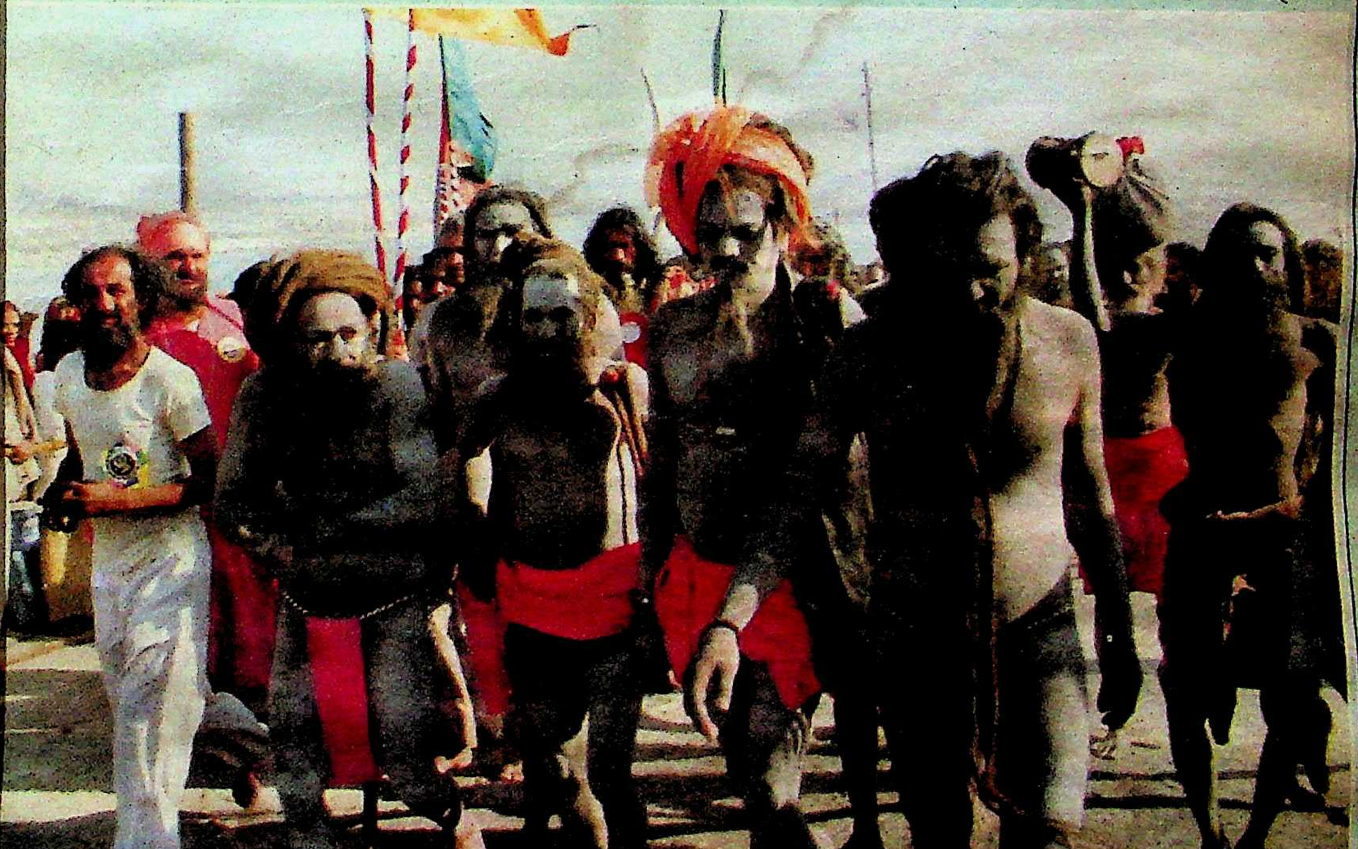

स्नान के लिए जाते हुए नागा साधुओं की टोली

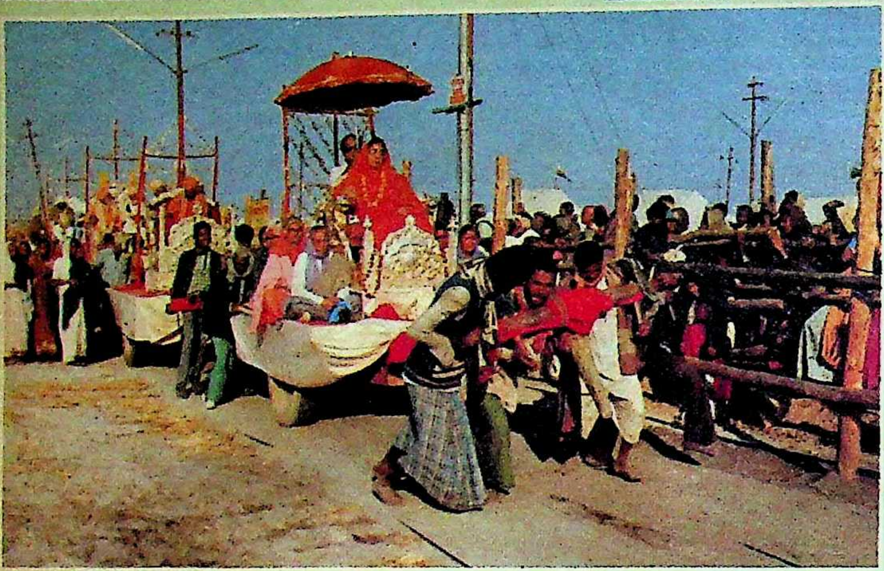

है कि मौनी अमावस्या तक भी यह काम पूरा हो सकेगा। गंगा को प्रदूषणमुक्त करने की बात तो करना ही फिजूल है, इस समय मेले में उपस्थित लोगों को पर्याप्त बिजली, सिर ढंकने की जगह, मल-मूत्रालय और पेयजल जैसी अनिवार्य सुविधाएं तक नहीं मिल रहीं। चैकर प्लेटों (लोहे की शीट) के उठे हुए किनारों में उलझ कर गिरने और फिर भगदड़ मचने का अंदेशा अलग से बना हुआ है। इस अर्धव्यवस्था या कुव्यवस्था और साधु-संतों में आध्यात्मिक उपलब्धियों के बजाय भौतिक प्रदर्शन के बावजूद संगम पर पारंपरिक धार्मिक क्रियाकलापों के दृश्यों की छटा बिखरी हुई है :

संन्यासिनों की शोभा-यात्रा (बायें)
संगम पर श्रद्धालुओं का समुदाय (नीचे)

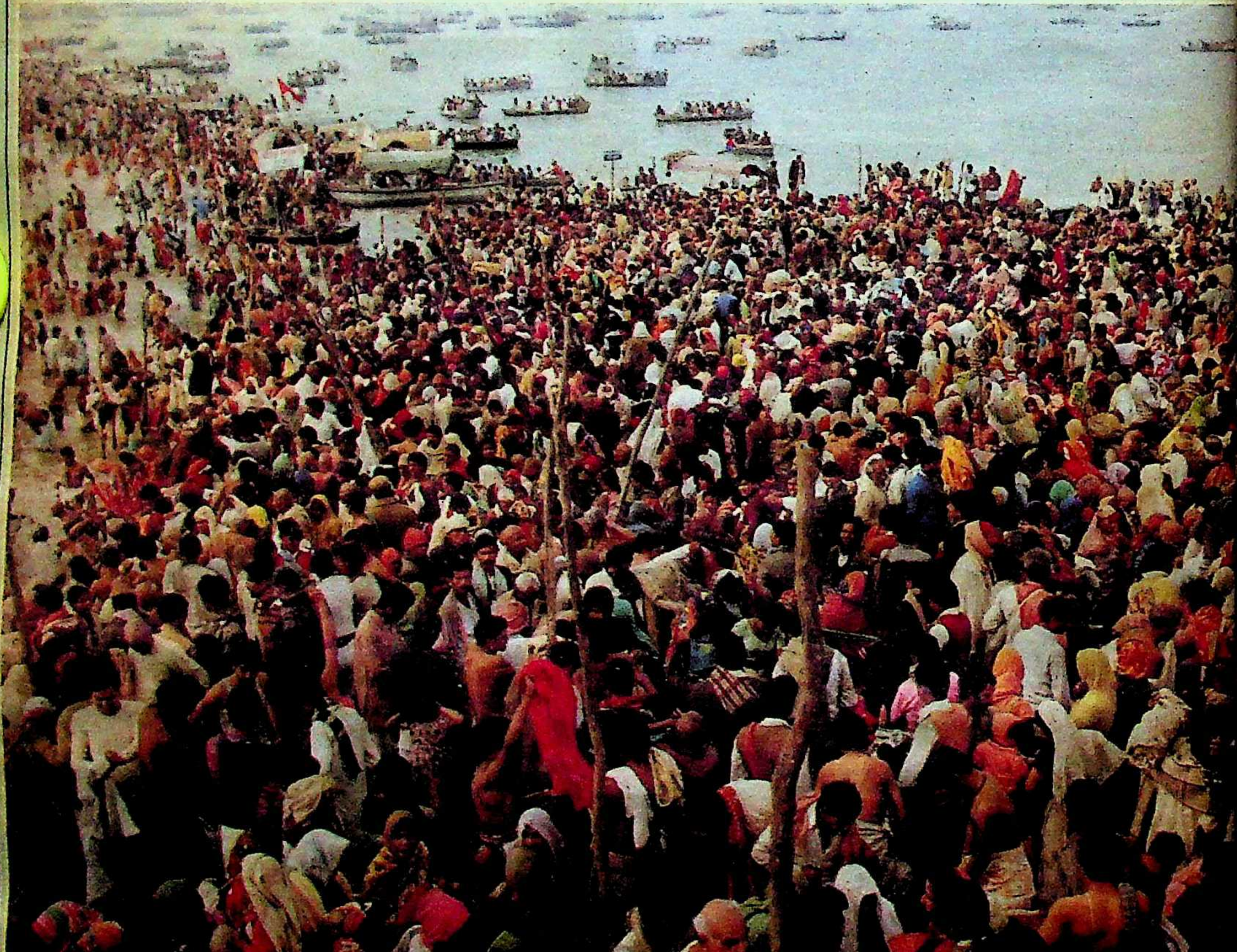

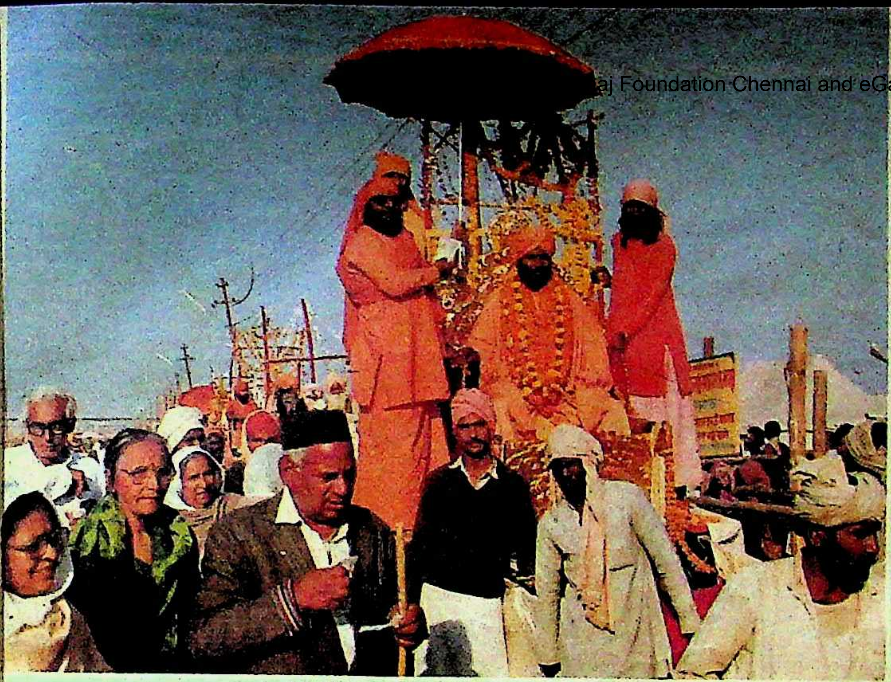

कुंभ मेले में महात्माओं का दल

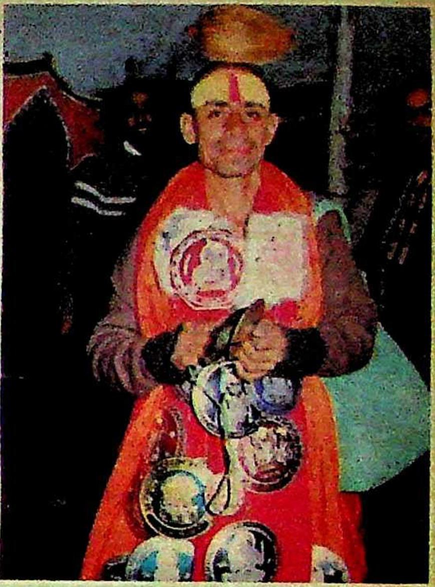

कुंभ मेले में गुजरात से आये हुए कन्हैया लाल महाराज माथे पर नारियल रखकर मजीरा बजा-बजाकर भजन गाते हैं। नाचते समय इनके सिर से नारियल नहीं गिरता। इन्हें नारियलवाले बाबा या मजीरे वाले बाबा के नाम से लोग जानते हैं।

छाया : वसीमुल हक

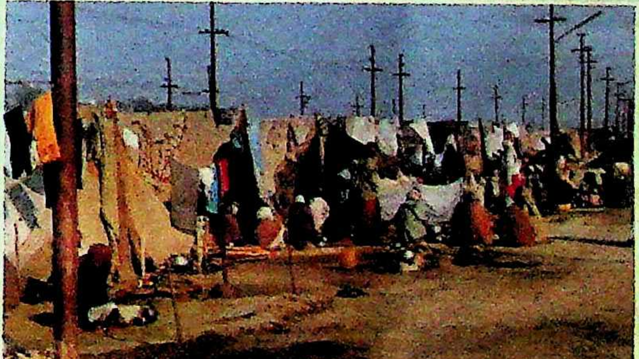

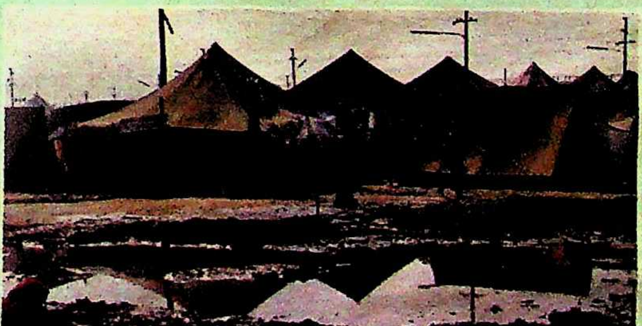

कल्पवासियों के तंबू गंदेनालों और उपेक्षित स्थान पर (बीच में) कल्पवासियों के तंबू के पास गंदेपानी का जमाव, कपड़ा धोती एक महिला (नीचे)

छाया : वसीमुल हक

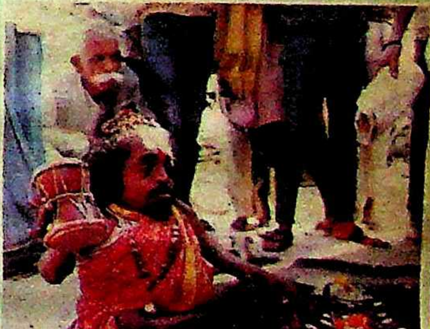

विलासनगर (नेपाल) से आये ५५ वर्षीय ढाई फुट के संन्यासी

छाया : वाईके जालान

छाया : सुनील सक्सेना

छाय
गिरीश श्रीवास्

दिल्ली में आयोजित १२वें फिल्मोत्सव में निर्माता एलवी प्रसाद दीप प्रज्ज्वलित करते हुए। साथ में डिंपल कपाड़िया और हरकिशन लाल भगत (बायें)। दर्शक-दीर्घा में राजेश खन्ना, डिंपल, राखी, रेखा, शशि कपूर, मनोज कुमार, अनुपम खेर।

केंद्रीय संचार मंत्री वीरबहादुर सिंह अपनी स्वर्गीय पत्नी चंपा देवी के त्रयोदश संस्कार के समय।

छाया : मनमोहन शर्मा

केहर-सतवंत की फांसी

मीडिया ने अहम मुद्दे क्यों नहीं उठाये ?

खबरनवीसों ने हाल के महीनों में केहर सिंह और सतवंत सिंह के मुकदमे की खबरें देने में मुस्तैदी तो खूब दिखायी, लेकिन इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुकदमे से जुड़े असली मुद्दे भूलकर वे या तो भावना में बहते रहे या दुनियाभर की बातों में भटक गये। ऐसा क्यों हुआ ?

केहर सिंह और सतवंत का मुकदमा तो ५१ महीनों तक खिचा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया ने पिछले आठ हफ्तों में इस मुद्दे पर विस्तार के साथ खबरें दी हैं। इस दौरान अदालत के सभी फैसलों, तर्कों और अर्जियों को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर सुर्खियां देकर छापा। इन खबरों को इतनी प्रमुखता देना सही भी था, क्योंकि यह एक प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा मुकदमा था। इसीलिए इस अवधि में अखबारों ने इससे जुड़े तमाम पहलुओं को छापने की होड़-सी लगा ली। सभी अर्जियों, क्षमादान-याचिकाओं और इन दोनों के परिवारों के सदस्यों द्वारा कही गयी हर बात को बहुत प्रमुखता देकर छापा गया। क्या ऐसा न्याय के प्रति चिंता से किया गया? या इससे जुड़े राजनीतिक पहलुओं तथा चुनावी वर्ष में शासक और विपक्षी दलों पर पड़ने वाले इसके असर को देखकर ऐसा किया गया? या फिर सिर्फ इस खबर को पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ाने के खयाल से ही छापा गया? जिस तरह से, हर मुद्दे पर विभाजित रहने वाले पत्रकारों ने इस मुद्दे पर एक समान मुस्तैदी दिखायी और वस्तुगत रिपोर्टिंग करने की जगह पाठकों की भावनाओं के मद्देनजर ही खबरें लिखीं, यह [illegible] आश्चर्यजनक है।

केहर की तरफदारी: महात्मा गांधी की हत्या के समय भी इतनी ही विस्तृत खबरें दी गयी थीं और इतनी ही प्रमुखता से। लेकिन जिस तरह से अखबारों, पत्रिकाओं ने अपने पाठकों को यह एहसास करा दिया कि केहर निर्दोष है और उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है, उसकी तुलना सिर्फ नानावती कांड के समय 'ब्लिट्ज' की रिपोर्टिंग से की जा सकती है। ले० कमांडेंट नानावती के मामले में 'ब्लिट्ज' ने ऐसी रिपोर्टिंग की थी कि उसका हर पाठक अदालती खंडपीठ का सदस्य-सा बन गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक जज स्व० बीएम सिन्हा (जो बाद में चीफ जस्टिस बने) का कहना था, "'ब्लिट्ज' की भावनात्मक रिपोर्टों और उससे पैदा दबाव को अगर न्यायपालिका महसूस न करे तो इसका मलतब उसका अमानवीय हो जाना होगा।" प्रसिद्ध आंख विशेषज्ञ डा० एनएस जैन की पत्नी विद्या जैन के भाड़े के हत्यारों के मुकदमे को भी अखबार-पत्रिकाओं में काफी जगह मिली थी, क्योंकि इस मामले में भी बड़े लोग शामिल थे। रहस्य, रोमांस, सेक्स, खेल आदि सारे मसाले

राष्ट्रपति को दी गयी क्षमा-याचिकाओं को बहुत प्रचारित किया गया। लेकिन अखबार-पत्रिका के किसी भी व्यक्ति ने यह सलाह नहीं दी कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार-याचिका दायर करनी चाहिए जिससे अदालत भी देख ले कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गयी। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कैसे कर सकता है? राष्ट्रपति ने यह क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से छानबीन कर ली है और अब वे इस मुद्दे पर विचार नहीं कर सकते?

केहर सिंह को फांसी

फैसले पर संदेह क्यों ?

"जो आदमी पंथ से वैर मोल लेगा, उसका यही हाल होगा।"

क्या ये शब्द किसी षड्यंत्रकारी के मन की बात बता देते हैं? अपने सहकर्मी नंदलाल मेहता को मात्र एक पंक्ति का संदेश देने वाला आदमी अब फांसी पर चढ़ चुका है। उसके अंतिम शब्द थे: 'जो बोले सो निहाल, सत्श्री अकाल।' वह आदमी था आपूर्ति एवं निबटान महानिदेशालय में असिस्टेंट, केहर सिंह।

केहर सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने का दोषी बताया गया था। नफरत और नाराजगी जाहिर करनेवाला उपरोक्त वाक्य उसने ३१ अक्तूबर, १९८४ को १० बजकर ४५ मिनट पर अपने दफ्तर की तीसरी मंजिल के बरामदे में कहा था। कुछ ही मिनट पहले श्रीमती गांधी को गोली मारी गयी थी। जस्टिस जगन्नाथ शेट्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में कहा है, "उसे (केहर को) इस हादसे के सारे विवरण ज्ञात थे और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह इस खबर की प्रतीक्षा ही कर रहा था। यह ध्यान देने की बात है कि उस समय (१०.४५ बजे) बाहर किसी भी आदमी को यह खास सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री को किसी सिख ने गोली मारी है या किसी और ने। केहर सिंह को सारी बातों का पता था, वरना वह इन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करता।" सुप्रीम कोर्ट की पीठ के उनके साथी जज जे ओझा ने भी माना, "यह प्रतिक्रिया उसके (केहर के) अंदर की अपराधी सोल (आत्मा) को बताती है जो बेअंत सिंह के साथ बनी थी।" किंतु केहर के बारे में दिये गये फैसले पर देश-विदेश में तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं। दरअसल अभी तक तीनों अदालतों—सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये 'एक रायवाले' किसी दूसरे फैसले की इतनी आलोचना नहीं हुई थी और उससे इतने संदेह नहीं पैदा हुए थे।

बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों, वकीलों और यहां तक कि अवकाश प्राप्त जजों ने भी केहर सिंह को फांसी दी जाने पर गंभीर शंकाएं उठायी हैं और कहा है, "अगर केहर सिंह को फांसी की सजा पर अमल होता है तो यह घटना हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक होगी।" पंजाब से तो और तीखी प्रतिक्रियाएं आयीं जहां केहर सिंह को 'अन्याय का शिकार हुए शहीद' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

केहर के खिलाफ लगाये गये आरोप इस प्रकार थे: वह धर्मांध व्यक्ति था और 'आपरेशन ब्ल्यू स्टार' कराकर अकाल तख्त को नुकसान पहुंचवाने के कारण वह श्रीमती इंदिरा गांधी से बहुत नफरत करता था। केहर, बेअंत की पत्नी का फूफा था, इसलिए वह बेअंत पर असर डाल सकने की स्थिति में था। 'आपरेशन ब्ल्यू स्टार' के बाद केहर अकसर बेअंत के घर जाने लगा था। दो या तीन बार दोनों ने अकाल तख्त को हुए नुकसान पर बातें भी की थीं।

श्रीमती गांधी की हत्यावाले साल (१९८४) जुलाई के आखिरी हफ्ते से अक्तूबर के तीसरे हफ्ते तक केहर सिंह और बेअंत सिंह की एक साथ चली तथाकथित 'गहन एवं गोपनीय' गतिविधियों, मंत्रणाओं और दिल्ली से अमृतसर तक की यात्राओं पर आधारित एक बुनी हुई लंबी कहानी के साथ अभियोग पक्ष ने अदालत में सबूत के तौर पर जो कुछ पेश किया, उसमें था केहर सिंह की मेज के दराज में पड़ा एक परचा, जिसका गुरुमुखी में शीर्षक था 'इंदिरा दी सिख', उसके घर से बरामद बेअंत सिंह का सोने का कड़ा और एक अंगूठी, बस। इनमें किसी भी चीज को श्रीमती गांधी की हत्या के षड्यंत्र में केहर सिंह के शामिल होने का 'पक्का प्रमाण' नहीं माना जा सकता था, न ही माना गया। एक अधिवक्ता का कहना है, "तीन महीने की अस्पष्ट गतिविधियों की अस्पष्ट कथा के सूत्रों को मिलाकर, खींचतान कर फैसले का आधार बना दिया गया। फैसले को यही बात विवादास्पद बनाती है।" कहना न होगा कि केहर सिंह की फांसी को लेकर उठे सारे संदेहों का आधार भी यही बात है।

श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा, यह विवाद कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन केहर को फांसी देना न्याय-प्रणाली को काफी दिनों तक परेशान करता रहेगा—न सिर्फ पक्के सबूतों के अभाव में उसे फांसी देने के लिए, बल्कि अपने बचाव का पूरा मौका न देने के लिए भी।

इंका से सहानुभूति रखनेवाले एक प्रमुख वकील ने पूरे मसले को इन शब्दों में रखा, "अगर आप बहुत बड़े सर्जन हैं और अपनी बीवी की हत्या कर देते हैं तो आप अधिक-से-अधिक आजीवन कारावास की सजा ही पायेंगे, लेकिन अगर आप किरानी हों और प्रधानमंत्री की हत्या में फंस जाएं तो आपको फांसी मिलेगी ही।"

—अभय अग्रवाल

इसमें शामिल थे। डा० जैन के पक्ष में शायद ही किसी ने लिखा हो। उलटे सबने उन्हें फांसी पर चढ़ा देने तक की मांग की। दो निर्दोष बच्चों की हत्या करने वाले अपराधियों, बिल्ला और रंगा को फांसी देने की मांग करते वक्त मीडिया ने कोई आड़-परदा भी नहीं रहने दिया।

लेकिन इस बार मीडिया केहर सिंह के पक्ष में आ गयी, शायद देश-विदेश के प्रमुख लोगों द्वारा उसका पक्ष लिये जाने के असर के कारण। इससे खुद मीडिया के अंदर यह संदेह पैदा हो गया कि क्या केहर सिंह सचमुच फांसी का हकदार है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कई प्रमुख न्यायविदों ने भी फांसी की जगह आजीवन कारावास देने की वकालत की।

पत्र-पत्रिकाओं के एक गंभीर पाठक की टिप्पणी है, "मुश्किल यह है कि मीडिया के लोग अकसर कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाते। उन्हें तो सिर्फ खबरों के लिए मसाला चाहिए।" केहर सिंह को फांसी देने जैसा मुद्दा जीवन और मरण के विषयगत मुद्दों से जुड़ जाने के कारण यह रूप ले लेता है।

असली मुद्दा गुम : इन सबके मिले-जुले असर और साथ ही चल रहे राम जेठमलानी के अभियान ने केहर सिंह के पक्ष में माहौल बनाया। फांसी के बाद अखंड पाठ और शोक-सभाएं आयोजित करने की खबरें भी उसी प्रमुखता से छपीं। जत्थेदार दर्शन सिंह रागी का यह बयान भी छपा कि केहर सिंह और सतवंत, "पंथ के सिपाही थे और वे पंथ के लिए शहीद हो गये।" इसे सारे अखबारों ने इतने विस्तार के साथ छापा कि मृत्युदंड के औचित्य वाला असली सवाल ही खो गया। रागी द्वारा उन दो लोगों को शहीद बताये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी जिन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या और हत्या का षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया था। सुप्रीम

कोर्ट के वकील सलमान खुर्शीद कहते हैं, "जब सुप्रीम कोर्ट बलबीर सिंह को छोड़ दे तो उसे ठीक और केहर सिंह को सजा सुना दे तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता।"

पत्र-पत्रिकाओं के एक गंभीर पाठक की टिप्पणी है, "मुश्किल यह है कि मीडिया के लोग अकसर कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाते। उन्हें तो सिर्फ खबरों के लिए मसाला चाहिए।" केहर सिंह को फांसी देने जैसा मुद्दा जीवन और मरण के विषयगत मुद्दों से जुड़ जाने के कारण यह रूप ले लेता है। जब मृत्युदंड की प्रासंगिकता के सवाल को उठाया जाना चाहिए था, मीडिया ने सतवत और केहर की क्षमा-याचिकाओं को ही उछाला। सतवंत सिंह के वकील आरएस सोढी के अनुसार सतवंत के आखिरी शब्द थे, "किसी भी सिख के लिए इससे बढ़कर गौरव की बात कुछ और नहीं हो सकती कि वह हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपनी जान दे। मैं इस काम के लिए मरने के लिए बार-बार जन्म लेना चाहूंगा।"

न्यायिक हत्या का मुद्दा : केहर सिंह का बेटा राजिंदर सिंह कह सकता था, "यह न्यायिक हत्या है...राष्ट्रपति ने उस प्रधानमंत्री की सलाह पर क्षमा-याचिका पर विचार नहीं किया जो अपनी मां की हत्या होने के कारण पूर्वग्रह से ग्रस्त है। उनकी हत्या किसी और ने की...।' यह बयान उस बेटे का है जिसका दुखी होना स्वाभाविक था और जिसका दुख उसके विवेक से भारी पड़ सकता है। किंतु किसी भी अखबार ने यह सवाल नहीं उठाया कि यह सजा किस तरह 'न्यायिक हत्या' है और राजिंदर सिंह ने कैसे कह दिया कि हत्या किसी और ने की। जो आदमी इस फैसले से प्रभावित हुआ हो, उसके पूर्वग्रहों को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन क्या यह मीडिया की जिम्मेवारी नहीं थी कि वह इस भावनात्मक तूफान के दौर में विवेक नहीं खोकर अपना काम करती? इसी भावनात्मक तूफान के दौर में, जो तुरंत उतर भी जायेगा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को भुला दिया गया। मौजूदा परिस्थितियों में इसे बहुत सही (और नाटकीय) तरीके से उठाया जा सकता था। यह गलती खुद मीडिया के लोगों ने ही की है।

एक प्रधानमंत्री की हत्या उसकी सुरक्षा के लिए तैनात लोगों ने ही कर दी और ऐसी घटना आगे नहीं होनी चाहिए, इस बात को याचिकाएं दायर करते वक्त ध्यान में ही नहीं रखा गया। इसके विपरीत वरिष्ठ और तेज-तर्रार वकील राम जेठमलानी तथा संतुलित रिपोर्टिंग के लिए प्रशंसित दैनिक 'टाइम्स आफ इंडिया', तक ने असली मुद्दे को भुला दिया और एक-दूसरे के लिए गाली-गलौच तक की भाषा पर उतर आए (देखें बाक्स)। केहर सिंह के पक्ष में जनमत बनाने के लिए अखबार-पत्रिकाएं बहुत हद तक जिम्मेवार हैं, और जाने-अनजाने उन्होंने बचाव पक्ष के वकील की भूमिका में एक जन-अदालत ही लगा दी।

सतवंत के मुकदमे की सुनवाई और विशेष याचिका वापस लेने की खबरें पहले पृष्ठ पर तो छपीं, लेकिन उन्हें प्रमुखता नहीं दी गयी। दूसरी ओर १६ दिसंबर को जब केहर को फांसी देना रोक दिया गया और उसकी क्षमा-याचिका सुनवाई के लिए रख ली गयी, तो अगले दिन अनेक अखबारों ने इसी खबर को अपना 'लीड' बनाया। लेकिन मीडिया का यह अभियान निष्फल रहा।

लेकिन इस बार मीडिया केहर सिंह के पक्ष में आ गयी, शायद देश-विदेश के प्रमुख लोगों द्वारा उसका पक्ष लिये जाने के असर के कारण। इससे खुद मीडिया के अंदर यह संदेह पैदा हो गया कि क्या केहर सिंह सचमुच फांसी का हकदार है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कई प्रमुख न्यायविदों ने भी फांसी की जगह आजीवन कारावास देने की वकालत की।

अगर मारा गया व्यक्ति राष्ट्रीय महत्व का नेता होता है तो आम तौर पर यही होता है कि लोग उसके लिए जिम्मेवार लोगों को 'गोली से उड़ाने' की मांग करते हैं। महात्मागांधी, मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ केनेडी और ऐसे अनेक लोगों की हत्या के मामले में ऐसा ही हुआ है। लेकिन इस बार लोगों की सहानुभूति केहर को माफी देने की मांग, जो आजीवन कारावास के रूप में भी हो सकती थी, सें जुड़ गयी। ऐसा भारतीय जनतंत्र के चौथे स्तंभ की गलती से हुआ। अनेक प्रमुख दैनिकों में छपे संपादकीय से भी यही बात झलकती है।

रिपोर्ट दबाने का मामला : 'ट्रिब्यून' ने लिखा, "कुछ संदेह रह ही जाते हैं और यह हत्या के षड्यंत्र में केहर की भूमिका को लेकर हैं। यहां किसी के लिए यह मान लेना गलती होगी कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ने अपना फैसला देने के पहले सभी साक्ष्यों पर पर्याप्त गौर नहीं किया होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने राष्ट्रपति को ठक्कर आयोग की रिपोर्ट नहीं दी है, उससे उसकी मंशा पर संदेह बना ही रहता है।" इस मुद्दे को भी अन्य अखबारों के संपादकीय में कभी कायदे से नहीं उठाया गया। दरअसल इस मुद्दे को सरकार द्वारा यह रिपोर्ट दबायी जाने की गलती के रूप में ही उठाया जाना चाहिए था।

लेकिन मीडिया के लोग क्षमा-याचिकाओं, कुछ प्रमुख लोगों की बातों और बिकाऊ खबरों के लालच में आ गये। और इस मौके पर बुनियादी मसले को उठा पाने में असफल रहे। क्या केहर सिंह को आजीवन कारावास देने से उसे उचित सजा मिल जाती? क्या राष्ट्रपति अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक बाध्यताओं से ऊपर उठकर ऐसा फैसला दे सकते थे जिससे इससे भविष्य में भी इस सर्वोच्च पद को लेकर शक किया जाता? फिर मीड़िया के लोगों ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को दबा लेने के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? मृत्युदंड पर कोई राष्ट्रीय बहस भी नहीं छेड़ी जा सकी। जजों में भी इस मुद्दे पर मतभेद रहता ही है और जब सवाल किसी के जीवन से जुड़ा हो तो उसे एक व्यक्ति की राय पर नहीं छोड़ा जा सकता।

विवाद अब भी अहम : इससे जाहिर होता है कि किस तरह मीडिया के लोग इतनी सामान्य और फालतू बातों से प्रभावित हो जाते हैं, दुनिया की बातों के असर में आ जाते हैं और किसी को भी हीरो बनाने में लग जाते हैं। अधिक महत्व वाले राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करने की जगह वे शोक-संदेशों, निंदा-प्रस्तावों और रागी की तरह उगली गयी आग को भी छापने में लगे रहते हैं। फांसी देने से पैदा विवाद अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। राष्ट्रपति को दी गयी क्षमा-याचिकाओं को बहुत प्रचारित किया गया। लेकिन अखबार-पत्रिका के किसी भी व्यक्ति ने यह सलाह नहीं दी कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार-याचिका दायर करनी चाहिए जिससे अदालत भी देख ले कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गयी। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कैसे कर सकता है? राष्ट्रपति ने यह क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से छानबीन कर ली है और अब वे इस मुद्दे पर विचार नहीं कर सकते? अभी तक मीडिया ने इस सवाल को नहीं उठाया है कि राष्ट्रपति ने इसे अपना फैसला बताने की जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर सही किया या गलत?

केहर सिंह को फांसी देने से अन्याय होने का बखेड़ा खड़ा करनेवालों को इन सवालों का जवाब देना होगा जिससे भविष्य में इस तरह दोबारा कीचड़ उछालने का काम न हो। लेकिन मीडिया-जगत के लोग अभी भी बेकार के मुद्दों में ही उलझे हैं और वास्तविकता तथा तार्किकता से मुंह मोड़े हुए हैं। अगर मीडिया ने हर तरह के दबाव से प्रभावित होना जारी रखा तो ऐसा होगा भी, जैसा कि मीडिया इस बार अपने को पाक-साफ रखने में असफल रही है।

—विजय दत्त और अरुण वली

जनता दल

रैलियों की राजनीति

उत्तर प्रदेश का जनमत अपने पक्ष में बनाये रखने के लिए राजीव गांधी ने गत नवंबर में रायबरेली को तीन दिनों तक खूब गुलजार किया। जनवरी के शुरू में वीपी सिंह और जनता दल के अन्य नेताओं ने नहले पर दहला मारते हुए इटावा, बस्ती और रायबरेली में विशाल रैलियां कीं। आखिर किन हकीकतों को उजागर करती हैं ये रैलियां ?

जनाधार की तलाश : रायबरेली रैली के मंच पर (बायें से) अरुण नेहरू, वीपी सिंह, अजीत सिंह, पासवान

आसमान का मुकाबला : बारिश के बावजूद उमड़ी भीड़ का अभिवादन करते जनता नेता

रैलियों व जनसभाओं के जरिये विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार का जायजा लेना पुन: शुरू कर दिया है। वास्तव में इसे जनता दल के चुनावी अभियान का श्रीगणेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने २२ से २४ नवंबर, १९८८ तक अमेठी-रायबरेली की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान २२ नवंबर को रायबरेली के जीआईसी कालेज मैदान में जनसभा कर प्रदेश में अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। उनके इस दौरे के मकसद को भांपते हुए ही जनता दल के नेता सक्रिय हुए हैं।

राजनीतिक चुनौती : जनता दल के नेताओं ने चुनावी अभियान की विधिवत शुरुआत उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सर्वाधिक प्रबल नेता मुलायम सिंह यादव के गृह जनपद इटावा से ५ जनवरी १९८९ को की। इटावा राज्य का मध्यवर्ती जिला है। पिछड़े वर्ग के इस गढ़ का राजनीतिक महत्व विपक्ष के लिए इस वजह से और अधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव भी यहीं के हैं। इस लिहाज से देखें, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गृह जनपद में मुलायम सिंह यादव ने ७९ हजार से अधिक भीड़ जुटा कर उन्हें राजनीतिक चुनौती दी है। हालांकि इस जनसभा में वीपी सिंह, देवीलाल, अजीत सिंह, राम विलास पासवान, मेनका गांधी, जार्ज फर्नांडीस, शरद यादव सरीखे राष्ट्रीय नेताओं ने शिरकत की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ५ जनवरी को जनता दल की जीआईसी मैदान में जुटी भीड़ मुलायम सिंह यादव के प्रभाव से आयी थी, न कि जनता दल के वरिष्ठ नेताओं के नाम पर। लगभग ६ घंटे चली जनसभा में अकबर अहमद डम्पी, विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, रामशरण दास, जनेश्वर मिश्र तथा रेवती रमण सिंह भी मंच पर मौजूद थे। हां, चंद्रशेखर किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहने तथा रामकृष्ण हेगड़े बंगलौर से दिल्ली की हवाई उड़ान अचानक रद्द होने के कारण मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपनी शुभकामनाएं जरूर भेज दीं।

इटावा रैली के जरिये मुलायम सिंह यादव ने वीपी सिंह तथा अन्य नेताओं को भी अपनी शक्ति का अहसास कराया है। इटावा के समीपवर्ती जनपद मैनपुरी तथा कायमगंज (फर्रुखाबाद) से काफी भीड़ आयी थी। भिंड के प्रभावशाली ठाकुरों का एक धड़ा भी वीपी सिंह को सुनने यहां पहुंचा था। एटा तथा मैनपुरी में खासा प्रभाव रखने वाले तथा तीन बार कायमगंज से विधायक रह चुके अनवर मोहम्मद खां तथा उनके पुत्र युवा जनता दल के नेता अनवर जमाल खां काफी भीड़ जुटा लाये थे। स्वयं मुलायम सिंह यादव पंद्रह दिनों तक गांव-गांव

111153

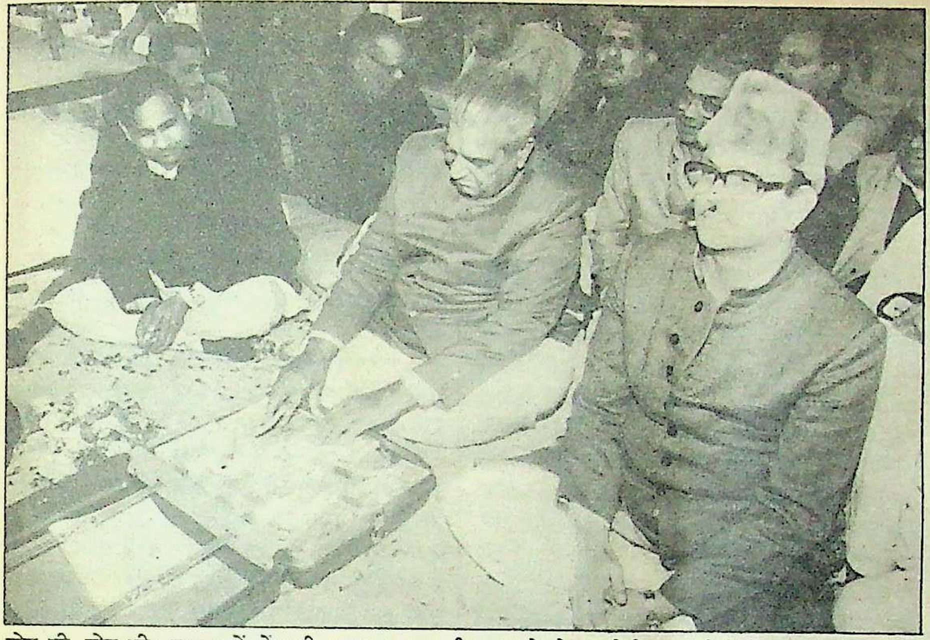

वोट भी, नोट भी : इटावा में भेंट की ७ लाख रुपए की रकम देखते हुए देवीलाल, वीपी सिंह, अन्य नेता

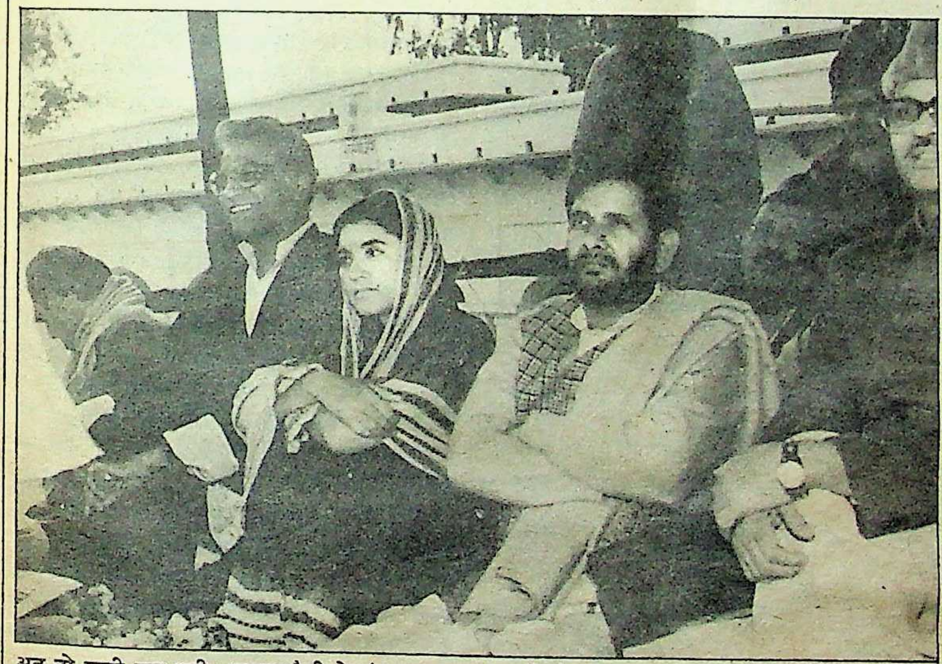

अब तो गाड़ी चल गयी : इटावा रैली के मंच पर जनता दल के नेता

जाकर जनसम्पर्क व चंदा एकत्र करते रहे थे। चार विधायकों—बाबूराम यादव, महाराज सिह, कमलेश पाठक, गया प्रसाद वर्मा तथा जिला युवा लोकदल के अध्यक्ष राम नरेश यादव ने भीड़ और चंदा जमा करने में पूरी ताकत लगा दी थी। इसके पीछे मकसद था कि मुलायम सिह यादव की प्रदेश स्तर पर प्रबलतम एवं सर्वमान्य विपक्षी नेता के रूप में छवि बनी रहे, ताकि उन्हें जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया जा सके। मुलायम सिह यादव का धड़ा अपने मकसद में काफी हद तक सफल भी हुआ है।

घात-प्रतिघात : जनता दल में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष-पद पाने के लिए जो उठापटक और जोड़तोड़ चल रही है, उसका खुलासा भी इस रैली के आयोजन ने किया। रैली के आयोजक मुलायम सिह यादव गुट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल यादव को आमंत्रित नहीं किया था। इसी प्रकार रामनरेश यादव, प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष मननेहर लाल सरीखे नेताओं की भी उपेक्षा की गयी थी। सत्यपाल यादव इटावा रैली में आये जरूर थे, किन्तु अजीत सिह का भाषण समाप्त होते ही वापस चले गये। यदि २ जनवरी को बस्ती में अजीत सिह ने सत्यपाल यादव पर दबाव डालकर उन्हें इटावा आने के लिए मजबूर न किया होता, तो आते ही नहीं। मंच पर चल रही इस चर्चा ने सत्यपाल यादव को बहुत क्षुब्ध किया कि वीपी सिह उनके स्थान पर रेवती रमण सिह को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं।

> देवीलाल ने अपनी ओर से इतना ही धन देकर इसे जनता दल के केंद्रीय कोष में जमा करने को कहा। देवीलाल ने जनता से एक नोट और एक वोट की मांग की। उन्होंने कहा, "यह राज्य कांग्रेस का नहीं, पांच सितारा हुकूमत का है जिसके नंबरदार कहीं उद्योग स्टार, कहीं फिल्म स्टार और कहीं दून स्टार हैं। किसानों को तख्तताज के साथ ही रिवाज भी बदलने होंगे।" इंदुभाई पटेल, सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा शहाबुद्दीन द्वारा जनता दल का विरोध करने के बारे में देवीलाल का कहना था, "अब जनता दल की गाड़ी चल गयी है, जो चढ़ गया सो चढ़ गया, जो रह गया सो रह गया।"

इटावा में वीपी सिह के तेवर देख कर आभास हुआ कि वे एक बार फिर से आक्रामक हो उठे हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही इस वाक्य से की, "अब तक नौकरी तबादला, तरक्की के बिकने की बात सुनी जाती थी, मगर यह सरकार इस देश का ईमान और शान भी बेचने लगी है।" मुलायम सिह यादव ने देवीलाल को पूर्व घोषित ५ लाख के बजाय सात लाख की थैली दी। देवीलाल ने अपनी ओर से इतना ही धन देकर इसे जनता दल के केंद्रीय कोष में जमा करने को कहा। देवीलाल ने जनता से एक नोट और एक वोट की मांग की। उन्होंने कहा, "यह राज्य कांग्रेस का नहीं, पांच सितारा हुकूमत का है जिसके नंबरदार कहीं उद्योग स्टार, कहीं फिल्म स्टार और कहीं दूत स्टार हैं। किसानों को तख्तताज के साथ ही रिवाज भी बदलने होंगे।" इंदु भाई पटेल, सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा शहाबुद्दीन आदि द्वारा जनता दल का विरोध करने के बारे में देवीलाल का कहना था, "अब जनता दल की गाड़ी चल गयी है, जो चढ़ गया सो चढ़ गया, जो रह गया सो रह गया।" अजीत सिह ने भी एकता में टांग अड़ाने वालों पर प्रहार किया, "जनता दल तो बन गया, नेता दल वक्त पर देखा जायेगा।"

बस्ती रैली : इटावा रैली के तीन दिन पूर्व ही वीपी सिंह ने पूर्वांचल के महत्वपूर्ण जिले बस्ती में भी जनता दल की मजबूत पकड़ साबित की थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद वीपी सिंह ने २ जनवरी १९८९ को पहली बार बस्ती के जीआईसी मैदान में जनसभा की। बस्ती में वीपी सिंह के साथ अजीत सिंह, राम विलास पासवान और सत्यपाल यादव थे। इन नेताओं को सुनने के लिए लगभग एक लाख की भीड़ उमड़ आयी थी। १९८४ में जब वीपी सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो इसी जीआईसी मैदान से उन्होंने राजीव गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। उसके बाद बस्ती में अब यह किसी भी दल की सबसे बड़ी जनसभा थी। अजीत सिंह का गढ़ समझे जाने वाले बस्ती में इस जनसभा के आयोजन का सारा दारोमदार मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, दिवाकर विक्रम सिंह, सुखपाल पांडेय तथा माता प्रसाद पांडेय आदि विधायकों पर था। लेकिन आयोजन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में प्रसिद्ध पाल सिंह और लक्ष्मेश्वर सिंह थे। ये दोनों संजय सिंह के खास माने जाते हैं। वैसे पूर्व विधायक बाबूराम वर्मा, पूर्व सांसद ब्रज भूषण तिवारी ने भी भीड़ जुटाने में काफी मदद की थी। इस जनसभा में भी जनता दल के आपसी झगड़े की झलक मिली। विधायक माता प्रसाद पांडेय तथा सुखपाल पांडेय को सभा मंच पर स्थान ही नहीं दिया गया। विधायक दिवाकर विक्रम सिंह सभा स्थल पर ही नहीं आये और मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ को सिर्फ मिनट भर के लिए ही बोलने का समय दिया गया। इस कारण अजीत सिंह-घटक के लोगों को लगा कि उन्हें जनता दल में उपेक्षित किया जा रहा है।

रायबरेली रैली : रायबरेली के जीआईसी मैदान में आठ जनवरी को हुई जनता दल की रैली में भी पार्टी में चल रहे घटकवाद की छाया साफ दिखी। अरुण नेहरू के कहने पर इस रैली का आयोजन उनके स्तम्भ समझे जाने वाले अखिलेश सिंह तथा अमवां के ब्लाक प्रमुख अशोक सिंह ने किया था। दरअसल, इस जनसभा के जरिये जहां अरुण नेहरू अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की प्रतिक्रिया जनाना चाहते थे, वहीं वीपी सिंह और संजय सिंह कांग्रेस का गढ़ रह चुके इस जिले में जनता दल का जनाधार खोज रहे थे। जनता दल की यह जनसभा राजनीतिक हलकों में सफल मानी जा रही है, क्योंकि दो दिन की लगातार वर्षा और कड़ाके की ठंड के बावजूद १९ नवंबर १९८८ को इसी मैदान पर हुई राजीव गांधी की जनसभा से अधिक भीड़ यहां आ जुटी थी। दोनों जनसभाओं में आयी जनता में फर्क यह था कि राजीव की जनसभा में लोगों को ढो कर लाया गया था और वहां भीड़ में पचास प्रतिशत सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन जनता दल के नेताओं को सुनने लोग स्वतः आये थे। हां, संजय सिंह के समर्थक ६ बसों में भरकर अमेठी से लोगों को जरूर लाये थे और सुलतानपुर के पूर्व विधायक रामसिंह जीपों के एक लम्बे काफिले में भीड़ लाये थे। इसके अतिरिक्त अखिलेश सिंह के प्रभाव से लालूपुर चौहान व महाराजगंज से लोग आये थे तथा वीपी सिंह के चहेते सरैनी के अशोक सिंह के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसभा में पहुंचे थे।

हालांकि ८ जनवरी की सुबह जब आरिफ मोहम्मद खान दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे, तो उन्हें जनसभा होने की आशा ही नहीं थी, क्योंकि मौसम बहुत खराब था। पानी लगातार बरस रहा था। अरुण नेहरू, वीपी सिंह और राम विलास पासवान को भी यही लग रहा था कि प्रतिकूल मौसम के कारण रैली शायद ही हो सके। खराब मौसम के कारण ही देवीलाल रायबरेली नहीं आ सके। पर आरिफ मोहम्मद खान, मुफ्ती मोहम्मद सईद, विद्याचरण शुक्ल, विजय सिंह मनकोटिया, रामनरेश यादव, सत्यपाल मलिक तथा जफर अली नकवी रायबरेली पहुंच गये थे। मुलायम सिंह यादव, मेनका गांधी और अकबर अहमद डंपी को छोड़कर इटावा रैली में मौजूद सभी नेता रायबरेली आये थे। मुलायम सिंह यादव को उसी दिन अचानक इटावा चला जाना पड़ा था, क्योंकि वहां जिला परिषद के चुनावों में उनके ही कुछ प्रत्याशी आमने-सामने हो गये थे। जनसभा में संजय सिंह ने राजीव और उनके साथियों को देशी अंग्रेज करार दिया। उनका कहना था कि विदेशी अंग्रेजों को भगा कर देश आजाद हुआ था और देशी अंग्रेजों को सत्ता से हटा कर जनता आजाद हो जायेगी। मुलायम सिंह यादव की गैरहाजिरी में उनके बाद लोकदल-ब में दूसरे नंबर के नेता बेनी प्रसाद वर्मा को वीपी सिंह ने विशेष महत्व दिया। राम विलास पासवान से जनसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा, "अब जिसे कांग्रेस में जाना है, चला जाये और जिसे जनता दल में आना है, हमारे साथ आ जाये, लेकिन बीच का रास्ता ठीक नहीं है।"

रायबरेली की जनसभा में वीपी सिंह ने जनता का उत्साह देख कर कहा, "जब जनता आसमान का मुकाबला करने को तैयार है, तो राजीव सरकार के पास अब अधिक समय नहीं बचा है।" जनसभा के बाद संवाददाताओं से सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता दल के ६० फीसदी प्रत्याशी पिछड़े वर्ग, हरिजन तथा अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। साथ ही यदि उनका दल सत्ता में आया, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता और अधिक अधिकार दिये जायेंगे। वीपी सिंह की बातों से लगा कि वे माने बैठे हैं कि अप्रैल तक आम चुनाव अवश्य हो जायेंगे। यदि ऐसा होता है, तो उत्तर प्रदेश जनता दल में चल रहे घटकवाद को समाप्त करने के प्रयास सबसे पहले होंगे।

१४ दिसंबर १९८८ को, जब संजय सिंह ने अमेठी से दिल्ली तक की पदयात्रा समाप्त करने के बाद बोट क्लब पर जनसभा की थी, तो अरुण नेहरू ने घोषणा की थी कि वे ८ जनवरी को रायबरेली की जनसभा में उन लोगों को मंच पर लायेंगे, जिन्हें विपक्ष की राजनीति करने के कारण सरकार ने प्रताड़ित किया है। पर न जाने क्यों रायबरेली में अरुण नेहरू ने स्थानीय मुद्दों को सभा में उठाने से मना कर दिया? इसका जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ा है। रायबरेली की जनसभा में वीपी सिंह ने जनता का उत्साह देख कर कहा, "जब जनता आसमान का मुकाबला करने को तैयार है, तो राजीव सरकार के पास अब अधिक समय नहीं बचा है।" जनसभा के बाद संवाददाताओ से सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में जनता दल के ६० फीसदी प्रत्याशी पिछड़े वर्ग, हरिजन तथा अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। साथ ही यदि उनका दल सत्ता में आया, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता व और अधिक अधिकार दिये जायेंगे।

वीपी सिंह की बातों से लगा कि वे माने बैठें हैं कि अप्रैल तक आम चुनाव अवश्य हो जायेंगे। यदि ऐसा होता है, तो उत्तर प्रदेश जनता दल में चल रहे घटकवाद को समाप्त करने के प्रयास सबसे पहले करने होंगे। क्योंकि इस समय जनता दल का जो हाल है, उससे जाहिर होता है कि भले ही ऊपर से एकता हो गयी हो, लेकिन अंदर से अभी तक एकता नहीं हो सकी है। अजीत सिंह धड़े के लोग मुलायम सिंह की काट कर रहे हैं और मुलायम सिंह खेमा सत्यपाल यादव की काट में लगा है। इस लड़ाई में जनता दल के रेवती रमण सिंह मुलायम सिंह के साथ हैं, ताकि वे सत्यपाल यादव के स्थान पर विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुरसी तक पहुंच सकें। जनमोर्चा के ही कुछ लोग अंदर-ही-अंदर संजय सिंह का विरोध करने में लगे हैं। यह सब कुछ हाल में हुई जनता दल की रैलियों में खुल कर सामने आया है। ऐसी परिस्थितियों में ही यदि चुनाव लड़ा जायेगा, तो सामंजस्य कैसे बैठेगा? हां, एक बात और स्पष्ट लगती है कि उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष की कुरसी मुलायम सिंह यादव के लिए लगभग पक्की हो गयी है।

—निशीथ जोशी,
इटावा, बस्ती और रायबरेली से

छाया-मनमोहन शर्मा

चुनाव सुधार विधेयक

सुधार का झंडा या सत्ता का हथकंडा ?

हाल के संसद-सत्र को बढ़ाकर ताबड़तोड़ शैली में पेश और पारित चुनाव सुधार विधेयक देशव्यापी चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जहां इसे एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम कहा है, वहीं विपक्ष ने इसे 'जबानी जमाखर्च, आधा-अधूरा और सत्ता-पक्ष के राजनीतिक स्वार्थों का एक हथकंडा' करार दिया है। प्रश्न यह है कि वर्षों पुरानी इस मांग पर चटपट अमल का कारण क्या था ? साथ ही इसकी निरंतर मांग करने वाले विपक्ष द्वारा अंततः मीनमेख निकालने की वजह क्या है ? प्रश्न यह भी है कि ये सुधार कितने मूलगामी और कारगर हैं तथा इनका देश के भावी राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ?

परदानशीन मतः मतदान करती एक महिला

लगभग तीन महीने पहले, यानी संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन के कुछ ही समय पूर्व, एयर इंडिया के वायुयान 'गोमती' में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एकाएक सूचना दी कि उनकी सरकार शीघ्र ही एक चुनाव सुधार विधेयक पेश करेगी। एक पत्रकार ने पूछा, "क्या यह विधेयक चुनाव आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगा ? प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा, "हमारा विधेयक बहुत व्यापक होगा। उसकी तुलना में चुनाव आयोग की सिफारिशें तो मात्र 'चिकन फीड' (चिड़िया का चुग्गा) हैं।" इसे याद करते हुए अब भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं, "तभी से मेरे मन में आशा जगी और हम बड़ी आतुरता से 'गज ग्रास' (एलिफेंट फीड) की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु आया तो केवल चींटी का दाना।"

प्रतीक्षा और निराशा का सामना करने वालों में आडवाणी अकेले नहीं, समूचा विपक्ष है। प्रतीक्षा का आलम तो यह रहा कि न केवल संसद के वर्षाकालीन सत्र का आना और खाली चला जाना लोगों को नागवार गुजरा, बल्कि शीतकालीन सत्र के अंतिम क्षणों तक यही प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा कि क्या इस सत्र में चुनाव सुधार विधेयक पेश होगा या नहीं ? अंततः सत्र को तीन दिन के अवकाश के बाद एक सप्ताह बढ़ाकर विधेयक प्रस्तुत और पारित करा लिया गया। पर जो आया, वह संतोष के स्थान पर विवाद का मुद्दा ही बना। यद्यपि सरकार के ६२वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिये मताधिकार की उम्र २१ से घटाकर १८ साल करने के निर्णय का अधिकांश क्षेत्रों में भरपूर स्वागत हुआ है, किंतु चुनाव प्रणाली में सुधारों को विपक्ष और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने 'मुखौटा सुधार' ही माना है, बावजूद इसके कि कांग्रेसी स्वयं इन्हें जोरशोर से मूलगामी, क्रांतिकारी और दूरगामी करार दे रहे हैं।

सोलह साल की प्रतीक्षा : चुनावों में धन, बल व राजशक्ति के बढ़ते दुरुपयोगों के चलते चुनाव-सुधार की बात १९७२ में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, भी हो रही थी। जनता पार्टी के १९७७ में सत्ता में आने पर इस चर्चा ने और जोर पकड़ा। इस सिलसिले में अनेक सुधारात्मक कदमों पर ब्यौरेवार विचार भी हुआ। यहां तक कि दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति भी बनी थी जिसने यथासमय अपनी रिपोर्ट भी पेश की। इस पर विचार-विमर्श भी हुआ, किंतु जनता पार्टी में मतभेद बढ़ने और सरकार टूटने के कारण विधेयक ताक पर रख दिया गया। तब से यह मांग सत्तापक्ष व अन्य मंचों से भी दोहरायी गयी। श्रीमती गांधी के पुनः सत्तारूढ़ होने के बाद इस बारे में वायदे तो जरूर हुए, पर उन्हें कभी अमली जामा नहीं पहनाया गया।

राजीव गांधी के शासनकाल की शुरुआत ही सुधारों की बातचीत से हुई। जनवरी १९८५ में नवगठित संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने चुनाव-सुधारों की बात स्पष्टतया कही। किंतु तब से अब तक इस पर अमल के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं हुए। हां, समय-समय पर विचार-विमर्श, टीका-टिप्पणी और मांग अवश्य होती रही। विपक्ष के अनुसार इसमें सबसे बड़ी बाधा स्वयं कांग्रेस पार्टी ही रही। इस समय भी अंतिम क्षणों तक पार्टी के उधेड़बुन में रहने के समाचार हैं, हालांकि कांग्रेस के नवंबर के अधिवेशन में इस पर विचार-विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि पहले तो इस विधेयक की, सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य विधेयकों की तरह से, कोई पूर्व-घोषणा नहीं थी। और जब हुई भी, तो सत्र समाप्ति

के अंतिम क्षणों में। निर्णय के लिए सत्र समाप्ति की पूर्वसंध्या पर कैबिनेट की एक आपात बैठक हुई जिसमें विधेयक को इसी सत्र में प्रस्तुत करने का फैसला हुआ। एक ओर तो विधि मंत्रालय को चटपट विधेयक तैयार करने के आदेश जारी हुए, दूसरी ओर सत्र बढ़ाने के। चूंकि विधि मंत्रालय को कुछ समय चाहिए था, इसलिए सत्र कुछ दिनों के अवकाश के बाद पुनः चला। चुनाव-सुधार की जितनी चर्चा सदन के भीतर हुई, उससे कहीं ज्यादा बाहर। आडवाणी के अनुसार, "आज १६ साल बाद जब इस दिशा में निर्णय लिया, तो उसको सत्तापक्ष वाले ऐसा उछाल रहे हैं मानो देश पर बड़ी भारी अनुकंपा कर दी हो।"

प्रधानमंत्री व उनकी सरकार इसे अनुकंपा मानते हों अथवा नहीं, किंतु ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम अवश्य मानते हैं। तभी सदन में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को 'चौथा कदम' बताते हुए कहा, "दलबदल विरोधी विधेयक, कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिये जाने को कानूनी मान्यता और धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग रोकने वाले कानून के रूप में 'तीन कदम' पहले ही उठाये जा चुके हैं।" कदाचित कुछ अधिक श्रेय स्वयं लेने की गरज से प्रधानमंत्री यह भी कह बैठे, "चालीस वर्षों में पहली बार इस पारित विधेयक ने चुनाव-सुधार के बड़े मुद्दों को छुआ है।" इस पर एक हाजिरजवाब राजनीतिक की टिप्पणी थी, "इस समूचे काल में शासन न केवल प्रधानमंत्री की पार्टी कांग्रेस का ही रहा, बल्कि स्वयं उनके वंश का भी।"

सरकार की लाचारी: चुनाव-सुधार संबंधी सारा श्रेय कांग्रेस अपने अग्रिम दस्तों-युवा कांग्रेस और राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) को देने पर आमादा है। ऐसा करते हुए वह कदाचित इस तथ्य को लील जाना चाहती है कि सुधार संबंधी विपक्षी मांग वर्षों से चली ही आ रही है और गत वर्ष विपक्षी दलों ने संयुक्त बैठक कर इस संबंध में १८ सूत्री मांगपत्र भी पेश किया था। यही नहीं १९८५ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सत्य गोपाल मिश्र ने मतदाताओं की आयु घटाने संबंधी एक विधेयक भी प्रस्तुत किया था जिसे विचार-विमर्श से निरंतर दूर रखा गया। अंततः विधि मंत्री बी० शंकरानंद को यह संशोधन विधेयक इस ढंग से प्रस्तुत करना पड़ा कि मिश्र का पूर्वप्रेषित विधेयक स्वयमेव रद्द हो जाये। प्रश्न यह उठता है कि इतने दिनों इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखने के उपरांत इस विधेयक को एकाएक पेश और पारित किन कारणों से किया गया?

जहां तक विधेयक पारित होने का प्रश्न है वह तो निश्चित ही था। कारण इसकी प्रस्तुति प्रचंड बहुमत वाले सत्तापक्ष द्वारा हुई थी, तो विपक्ष की यह पुरानी मांग थी। रही इस समय उसे पेश करने की बात, तो वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद विट्ठल गाडगिल के अनुसार, "यह हमारा पुराना वायदा था जिसे जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए

साक्षात्कार/ विट्ठल नरहरि गाडगिल

विपक्ष को खल रही है हमारी फतह

माया: ***मौजूदा चुनाव सुधार विधेयक सहसा पारित कराना क्या इस समय बुरी तरह घिरी सरकार की अपनी छवि मांजने-चमकाने की एक राजनीतिक चाल नहीं है?***

गाडगिल: *यह विधेयक सहसा नहीं लाया गया है। यह हमारे पुराने वायदे का अमली रूप है। १९८४ में हमारी नयी सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति के भाषण में जिन सुधारों का विवरण था, चुनाव सुधार उसी का एक अंश है। इसमें हुई देरी का कारण यह है कि इसके पूर्व हमने दलबदल विरोधी कानून, कंपनी कानून आदि पास कराये। इस बीच निरंतर चुनाव-सुधार के विभिन्न पहलुओं को जांचा-परखा गया और इस संबंध में पक्ष-विपक्ष में लंबी बातचीत चली।*

माया: ***किंतु इसे जिस समय व जिस ढंग से लाया गया है, क्या इसके पीछे कांग्रेस द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने का मंशा सर्वोपरि नहीं रहा है?***

गाडगिल: *राजनीतिक लाभ उठाने का कहां से सवाल उठता है, जबकि जोर-शोर से चर्चा चल रही है कि १८ वर्ष की आयु के जो नये मतदाता बनेंगे, वे कदाचित कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं? हमारे साथियों—मसलन वीरेंद्र पाटील ने संसद में मतदाता की आयु-घटाने का सीधे विरोध किया है। फिर भी हमने तमाम पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करके लोकतंत्र के हित में तथा बिना हानि-लाभ सोचे अपने वायदों पर अमल की दिशा में यह कदम उठाया है।*

माया: ***किंतु विपक्ष का आरोप है कि सुधार मूलगामी न होकर मात्र लीपापोती है और विद्यमान तीन कुरीतियों धन, बल व राज-शक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया?***

गाडगिल: *बल-शक्ति पर नियंत्रण के लिए हमने और कड़े दंड का प्रावधान किया है। इसके साथ राज-शक्ति को कम करने के लिए चुनाव आयोग का अधिकार-क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया है। यह अवश्य है कि हमने सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, क्योंकि व्यापक विचार-विमर्श से यही निष्कर्ष निकला कि यह निदान रोग से अधिक घातक होगा, क्योंकि धन के दुरुपयोग की रोकथाम की जगह यह धन-शक्ति को और बढ़ा देगा।*

माया: ***यदि चुनाव आयोग के अधिकार-क्षेत्र को बढ़ाने का आपका दावा सही है, तो उसे अधिक कारगर बनाने के लिए ३ मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मांग सरकार ने क्यों ठुकरा दी?***

गाडगिल: *विपक्ष स्वयं इस संबंध में भ्रमित है। एक ओर जहां वह टीवी-रेडियो की स्वायत्तता की मांग करता है, वहीं चुनाव आयोग के प्रति अपनी आशंका व्यक्त करता है। एक ओर वह चुनाव के समय मुख्य आयुक्त के अधीन 'केयर टेकर' सरकार चलाने की मांग करता है, तो दूसरी ओर चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर वह संदेह व्यक्त करता है। लगता है कि विपक्ष को ऐसे चुनाव आयुक्त की खोज है जो हर समय और हर मुद्दे पर उसी का पक्ष ले।*

माया: ***विपक्ष को भय है कि कहीं चुनाव आयोग और आयुक्त सत्ता पक्ष के दबाव अथवा प्रलोभन के कारण निष्पक्षता न खो बैठे इसीलिए वें बहुसदस्यीय चुनाव आयुक्त की बात करा रहे हैं।***

गाडगिल: *सत्तारूढ़ दल के पक्ष में चुनाव आयोग के होने की बात होती, तो हाल के उपचुनावों-विशेषकर हरियाणा के उपचुनावों—पर हमारे खिलाफ उसके अनेक फैसले कभी नहीं जारी किये जाते। बावजूद इसके हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह नहीं। रही बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की बात, तो उसकी व्यवस्था संविधान में है और नया कानून बनाने की जरूरत नहीं। तमाम विचार-विमर्श के बाद निष्कर्ष यह निकाला गया कि इसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। दरअसल मौजूदा चुनाव सुधार विधेयक स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक क्रांतिकारी कदम है।*

माया: ***फिर विपक्ष इतना बावेला क्यों मचा रहा है?***

गाडगिल: *यह उनकी एक राजनीतिक चाल है। विपक्ष इस सकारात्मक कदम के खिलाफ होहल्ला मचाकर जममत को भरमाना और अपनी ओर करना चाहता है। किंतु असलियत यह है कि मैदान हमने फतह किया है और विपक्ष को यही खल रहा है।*

—र०क०

अमली जामा पहनाना आवश्यक था। वरन जनता इसे केवल चुनावी घोषणा ही करार देती।"

आश्चर्यजनक यह है कि लगभग यही बात विपक्ष भी कहता है, किंतु कुछ भिन्न नजरिये से। विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, "चार साल तो कुछ याद नहीं आया एकाएक सबको चुनाव सुधार, युवकों आदि की सुध हो आयी है।" जनता सांसद जयपाल रेड्डी का मानना है, "वर्तमान चुनाव सुधार विधेयक का मुख्य लक्ष्य ऐसा भ्रम पैदा करना है जिससे लगे कि राजीव गांधी दलाली के आरोपों के दलदल में फंसे नहीं हैं, बल्कि आज भी स्वयं पहलकदमी करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं।"

अधिकांश विपक्षी नेता चुनाव-सुधार विधेयक को राजनीतिक हथकंडा ही करार देते हैं। क्योंकि, जैसा गुरुपदस्वामी का कहना है, मूल समस्याओं—धन-शक्ति, सत्ता-शक्ति, प्रचार-शक्ति और गुंडा-शक्ति—को तो स्पर्श भी नहीं किया गया है (देखिये साक्षात्कार)। जयपाल रेड्डी के अनुसार मतदाताओं की उम्र २१ से घटा कर १८ करने वाले जिस संविधान संशोधन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उस पर ही पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री को बाध्य होना पड़ा था। कारण, पार्टी में अंततः यह चिंता व्याप्त हो गयी कि मतदाताओं की सूची में जुड़ने वाले अधिकांश—साढ़े चार करोड़-नवयुवक मौका आने पर कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे। राजीव गांधी के लिए इस सार्वजनिक वायदे से मुंह मोड़ना संभव नहीं था और लाचार हो उन्हें विधेयक पेश करना पड़ा। विवशता की बात मार्क्सवादी सांसद सैफुद्दीन चौधरी ने भी 'माया' से बातचीत के दौरान कही, "अपनी नीतियों के चलते यह सरकार युवकों को किसी प्रकार सकारात्मक सामाजिक अथवा आर्थिक अधिकार देने में असमर्थ है। अतः उसने इसी में खैर समझी कि मतदान का अधिकार दे उन्हें कम से कम कुछ समय तक भरमाये रखें।"

कदाचित अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इस संशोधन को पारित करते समय पक्ष-विपक्ष ने इस तथ्य को पूर्णतया नजरअंदाज कर दिया कि इसके द्वारा वह राजनीति में नये सिरे से प्रवेश के लिए स्कूलों के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। विडंबना यह है कि इस मुद्दे पर ध्यान किसी और ने नहीं, सत्तापक्ष के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पाटील ने आकर्षित किया। पाटील का दावा है कि शिक्षा का गला घोटने वाली राजनीति अभी तक कालेजों तक ही सीमित थी, पर अब स्कूलों में फैलकर वातावरण को दूषित करेगी जिसके घातक और दूरगामी प्रभाव होंगे। किंतु उनका 'एकल स्वर' अनसुने तौर पर दब कर रह गया। इसके विपरीत एक ओर हंसी-मजाक में विवाह की आयु घटाने की मांग हुई, तो दूसरी ओर उम्मीदवारों की आयु घटाने की चर्चा। भाकपा के वरिष्ठ सांसद इंद्रजीत गुप्त ने प्रश्न किया कि यदि कानून मंत्री शंकरानंद के अनुसार देश के युवाओं में राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने की क्षमता है, तो उसी अवस्था में उसे चुनाव में भाग लेकर सदन में बैठने

साक्षात्कार/ **गुरुपदस्वामी**

यह केवल लीपापोती है।

मायाः आप की दृष्टि से, चुनाव सुधार विधेयक को सहसा संसद का सत्र बढ़ाकर पेश व पारित किये जाने का क्या कारण था?

गुरुपदस्वामीः *पहली बात तो यह है कि राजीव गांधी जिस चुनाव सुधार की बात पिछले दो-तीन वर्षों से करते आये हैं, उसे यदि इस समय सचमुच लागू न करते तो, अगले चुनाव में उनके खिलाफ यह एक मुद्दा बन जाता। दूसरे, स्वयं चुनाव आयोग ने इस संबंध में सरकार को कई सिफारिशें भेजी थीं, क्योंकि भ्रष्टाचार, मतदान पर कब्जे तथा दादागिरी के चलते निष्पक्ष चुनाव कराना उसके लिए संभव नहीं रह गया था। स्वयं कांग्रेसी भी चुनाव-सुधारों के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे थे। इसके अलावा वर्तमान प्रतिकूल माहौल में राजीव गांधी ने कदाचित यह सोचा होगा कि यदि वह मतदाता-आयु घटा देंगे, तो ४.५ से ५ करोड़ के करीब जो नयें मतदाता तैयार होंगे, वे अगले आम चुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे।*

मायाः ***क्या सचमुच इससे कांग्रेस लाभान्वित होगी?***

गुरुपदस्वामीः *मैं नहीं समझता कि उसे इसका लाभ मिलेगा।*

मायाः ***इसका कारण क्या है?***

गुरुपदस्वामीः *चुनाव-सुधारों की मांग विपक्ष वर्षों से करता आ रहा है। साथ ही विपक्ष-शासित राज्यों—मसलन कर्नाटक, प० बंगाल—के स्थानीय चुनावों में मतदाता-आयु घटाकर १८ वर्ष पहले ही कर दी गयी थी। इसलिए इसका श्रेय विपक्ष को पहले ही प्राप्त है।*

मायाः ***आप वर्तमान चुनाव-सुधारों से कितने संतुष्ट हैं?***

गुरुपवस्वामीः *मौजूदा सुधार-प्रस्तावों से मैं कतई संतुष्ट नहीं। इसके कुछ मुद्दों, जैसे—मतदाता-आयु घटाने, इलेक्ट्रानिक चुनाव मशीनों का प्रावधान आदि, का तो मैं समर्थक हूं। किंतु चुनाव की जो तीन कुरीतियां हैं—राज्य-शक्ति, धन-शक्ति और बल-शक्ति, उन्हें पूरी तरह नजरंदाज किया गया है। जब तक इन पर लगाम नहीं लगायी जाती तब तक स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। इस मापदंड से वर्तमान चुनाव-सुधार सीमित, संकुचित, अपर्याप्त और अप्रभावी हैं।*

मायाः ***क्या इन तीनों कुरीतियों की रोकथाम संभव है?***

गुरुपदस्वामीः *सरकार द्वारा चुनाव-खर्च वहन करने, पार्टियों के हिसाब-किताब की जांच करने, राजनीतिक दलों द्वारा लिये जाने वाले काले धन पर अंकुश आदि द्वारा निश्चित रूप से रोकथाम की जा सकती थी।*

मायाः ***जहां तक सरकार द्वारा चुनाव-खर्च वहन करने का सवाल है, बोगस उम्मीदवारों को इसी बहाने धन बटोरने से कैसे रोका जा सकेगा?***

गुरुपदस्वामीः *सरकार द्वारा खर्च वहन करना राजनीतिक पार्टियों के लिए है, स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए नहीं। इसलिए धन के ऐसे दुरुपयोग का सवाल ही नहीं। वैसे भी धन नकदी की जगह पोस्टर, पोस्टेज आदि के रूप में मुहैया किया जा सकता है।*

मायाः ***किंतु कांग्रेस का कहना है कि सरकार द्वारा चुनाव-खर्च वहन करना बेहद महंगा साबित होगा?***

गुरुपदस्वामीः *इससे कहीं अधिक महंगा भ्रष्ट लोकतंत्र साबित होगा। इसी धन-शक्ति से बल-शक्ति भी जुड़ी है। इसलिए जरूरी है कि चुनावों में भ्रष्ट तरीके अपनाने वालों को कड़ी सजा दी जाये।*

मायाः ***राज-शक्ति से कैसे निपटा जा सकता है?***

गुरुपदस्वामीः *चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी सरकारी साधनों का दुरुपयोग न करे, यह सुनिश्चित होना चाहिए। मसलन टीवी, रेडियो द्वारा मनमाने प्रचार की उसे सुविधा नहीं होनी चाहिए। विपक्षी पार्टियों को भी इन प्रसार माध्यमों के समान उपयोग का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार चुनावों के ऐन पहले अनुदानों, योजनाओं को शुरू करने पर रोक लगनी चाहिए।*

मायाः ***मौजूदा चुनाव सुधार विधेयक कितने कारगर साबित होंगे?***

गुरुपवस्वामीः *मौजूदा चुनाव सुधार विधेयक महज लीपापोती हैं। इसमें नाममात्र के कदम उठाये गये हैं। चूंकि इससे तीनों जबर्दस्त चुनाव कुरीतियों—धन-शक्ति, बल-शक्ति व राज्य-शक्ति पर रोक नहीं लगायी गयी है, इसलिए ये आगामी चुनावों में आंशिक रूप से ही कारगर साबित होंगे।*

—र०क०

का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? दोनों ही मांगें और तर्क अंततः ठुकरा दिये गये।

विपक्ष का संदेह: यदि ६२वां संविधान संशोधन निर्विरोध पारित हुआ, तो जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर जमकर विरोध और बहस हुई। विधेयक की १६ धाराओं पर सत्ता और विपक्ष की ओर से ६५ संशोधन पेश हुए, जो विधेयक के अधूरेपन और आवश्यक संशोधनों की गुंजाइश का स्पष्ट संकेत है। यह दूसरी बात है कि इनमें से मधु दंडवते द्वारा प्रेषित एक संशोधन, चुनाव प्रचार में धार्मिक स्थलों के उपयोग पर रोकथाम, के अतिरिक्त अन्य किसी संशोधन को स्वीकृति नहीं मिली। सरकारी मंशा के प्रति संदेह का बीजारोपण यहीं से आरंभ हुआ।

सदन के भीतर-बाहर बोलने वाले सांसदों ने प्रस्तुत प्रावधानों को न केवल सतही, लंगड़ा और नाकाफी बताया, बल्कि विपक्ष पर अंकुश लगाने वाला ठहराया। तेलुगू देशम के सी माधव रेड्डी ने सरकार पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि वह सिर्फ उन्हीं सुधारों को लेकर आयी है, जिनमें उसका फायदा है। उन्होंने सरकार को विपक्षी दलों की साझा बैठक बुलाकर विस्तार से चर्चा की जरूरत पर जोर दिया।

सूचना-प्रसारण मंत्री हरिकिशनलाल भगत के अनुसार प्रत्येक विपक्षी दल से इस संबंध में विस्तृत बातचीत पहले ही हो चुकी थी। अतः उनकी राय-सलाह न लेने का आरोप गलत है। जवाब में गुरुपदस्वामी ने कहा, "विपक्ष के साथ सलाह-मशविरे की संपूर्ण कसरत केवल खानापूरी और आम जनता को मूर्ख बनाने की नीयत से प्रेरित थी।" 'माया' को उन्होंने बताया, "शंकरानंद और भगत की विभिन्न दलों के नेताओं से जो अलग-अलग बातचीत हुई, उस दौरान उन्होंने यह सुझाव पेश किया था कि समस्त विचार-विमर्श के आधार पर एक मूल दस्तावेज तैयार किया जाये जिसे बुनियाद बनाकर प्रधानमंत्री विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक में बातचीत कर आम सहमति बनायें। किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। कारण विपक्ष द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले अनेक मूल प्रश्नों का उनके पास कोई तर्कसंगत व न्यायोचित उत्तर ही नहीं था।"

विधेयक के अनेक आपत्तिजनक प्रावधानों में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का मुद्दा विशिष्ट है। विपक्ष ही नहीं, प्रसिद्ध राजनीतिक पर्यवेक्षक एजी नूरानी का भी मानना है कि जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक की धारा २६ (अ) राजनीतिक दलों के लिए फांसी के फंदे से कम नहीं। इस धारा के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग में अपने को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। विचारणीय बात यह है कि चुनाव चिह्न आदेश के तहत एक प्रकार का पंजीकरण वैसे भी होता है। अतः यह विशिष्ट धारा क्यों? विशेषकर तब जबकि अनेक प्रावधानों को अस्पष्ट छोड़ दिया गया है?

माकपा सांसद सैफुद्दीन चौधरी इसके द्वारा चुनाव आयोग को दिये जाने वाले तरह-तरह के पूछताछ व जानकारियों के अधिकारों को सरकार की बदनीयती का सीधा सबूत करार देते हैं। धारा २६ (अ) चुनाव आयोग को इस निर्णय का अधिकार देती है कि वह राजनीतिक दलों की नीतियों की जांच-पड़ताल कर यह निर्धारित करे कि वह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर अमल करते हैं या नहीं? उल्लेखनीय है कि सदन में 'समाजवाद' की कसौटी का कड़ा विरोध स्वयं माकपा और भाकपा के वरिष्ठ नेताओं, सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्त ने किया। मधु दंडवते के अनुसार यदि यह प्रावधान पहले होता, तो स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी।

सत्ता दल के अनुसार यह शर्त [illegible] मकसद से लगायी गयी है कि सांप्रदायिक और अलगाववादी दलों को चुनाव-प्रक्रिया से दूर रखा जाये। किंतु 'समाजवाद' शब्द की दोटूक व्याख्या न होने के कारण चुनाव आयोग कौन-सा मापदंड इस्तेमाल करेगा? यह स्पष्ट न होने के कारण आशंका जाहिर की जाती है कि इसे पक्षपात के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित किया जा सकता है।

चुनाव आयोग किसी दल को पंजीकृत करे या नहीं, यह अधिकार तो उसे है ही, दल में किसी भी प्रकार के बदलाव की तुरंत सूचना आयोग को देना भी अनिवार्य बनाया गया है। चाहे वह बदलाव नाम में हो या काम में, पदाधिकारी में हो अथवा दफ्तर में, नीतियों में हो या लक्ष्यों में, चुनाव आयोग को फौरी सूचना देना आवश्यक है। इसे भी विपक्ष, विरोधी दलों पर अंकुश लगाने का मंशा ही मानता है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने 'माया' को बताया, "कदाचित इस प्रावधान के पीछे मंशा नवगठित जनता दल के पंजीकरण में अधिकाधिक बाधा उत्पन्न करना है।" जब इसकी चर्चा कांग्रेस के गाडगिल से चली, तो उन्होंने कहा, "ऐसे दलों को निश्चित ही तकलीफ होगी, जहां हर दूसरे दिन नाम और झंडे ही नहीं, पदाधिकारी भी बदल जाते हैं। आज वे चाहे कितना ही विरोध क्यों न करें, पंजीकरण का मुद्दा प्रारंभ में उन्होंने (विपक्ष ने) ही उठाया था। किंतु आपसी सिरफुटौवल में जुटी पार्टियों के लिए इसे स्वीकारना उतना ही कठिन होगा जितना कि जनमोर्चा जैसे संगठन के लिए यह बताना कि उनके कितने दफ्तर हैं और कहां-कहां?"

यह समस्या केवल विपक्षी दलों की ही नहीं, अधिकांश पर्यवेक्षक भी चुनाव-सुधार विधेयक में छिपे एक दमनकारी, पार्टी-नियंत्रण कानून को ही देखते हैं। एक पर्यवेक्षक का कहना है "इसके द्वारा आपातकाल के दौरान किये गये ४२वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद ३१-डी के उस प्रावधान की

राजीव गांधी

प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा, "हमारा विधेयक बहुत व्यापक होगा। उसकी तुलना में चुनाव आयोग की सिफारिशें तो मात्र 'चिकन फीड' (चिड़िया का चुग्गा) हैं।" लेकिन कानून मंत्री बी शंकरानंद तो मुद्दे की व्यापकता और क्लिष्टता के साथ यही दलीलें पेश करते रहे कि इतने विशाल और समस्याओं से भरे देश में चुनाव-सुधार जैसा काम एक झटके में करना असंभव है।

बी शंकरानंद

याद भी ताजा हो जाती है, जिसके तहत किसी भी दल को राष्ट्र-विरोधी करार देकर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान के स्व० राष्ट्रपति जिया-उल-हक के जिस प्रकार के आदेश को वहां के न्यायालय ने रद्द किया था, आज उसी प्रकार के कानून को भारतीय लोकतंत्र पर लादा जा रहा है।"

आयोग के अधिकार: चुनाव आयोग के 'स्वीकृत या अस्वीकृत करने' के अधिकारों को लेकर संसद के दोनों सदनों में लंबी बहसें चलीं। विपक्ष द्वारा रखी गयी बहुसदस्यीय आयोग की मांग तो प्रधानमंत्री ने 'चुनाव आयुक्त पर अविश्वास का द्योतक' कहकर ठुकराया ही, उसके (चुनाव आयुक्त के) अधिकारों को भी विस्तृत कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी के अनुसार धारा २८-ए के प्रावधानों की चर्चा न तो चुनाव आयोग से कभी हुई, न विपक्ष से और न ही स्वयं कांग्रेस पार्टी से। इस धारा के अनुसार चुनाव के दौरान उससे संबंधित राज्य के सभी कर्मचारी पूर्णतया चुनाव आयोग के मातहत हो जायेंगे। यदि इसका मकसद सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाना ही होता, तो कोई समस्या नहीं थी। किंतु विपक्ष को, उसके जरिये गैरकांग्रेस-शासित राज्यों पर अंकुश लगाने का मंशा अधिक दिखाई पड़ता है। जयपाल रेड्डी ने 'माया' से कहा, "सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के अधीन करना स्वागत-योग्य कदम है, पर इसके लिए आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता असंदिग्ध होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बहुसदस्यीय चुनाव आयोग की सिफारिश भी की थी और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के प्रतिनिधि की समिति का सुझाव भी पेश किया था।"

जहां तक आयोग की स्वतंत्रता का प्रश्न है, आयोग के विधि मंत्रालय के अधीन होने के कारण मुख्य आयुक्त की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और महालेखा परीक्षक (सीएजी) जैसी स्वतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की सिफारिश भी ठुकरा दी गयी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग का मुद्दा कांग्रेस कें हाल के नवंबर अधिवेशन के दौरान उठाया भी गया था और स्वीकारा भी। फिर अंतिम क्षणों में इसे नकारा क्यों गया? विपक्ष के अनुसार इसका सीधा कारण यह है कि किसी एक व्यक्ति को डरा-धमका कर अथवा लोभ-लाभ से प्रभावित किया जा सकता है। सदन में इस संबंध में दलीलें देते हुए सैफुद्दीन चौधरी ने पूर्व मुख्य आयुक्त श्यामलाल शकधर द्वारा 'माया' को ही दिये गये उस साक्षात्कार का हवाला दिया जिसमें उन्होंने इसका स्पष्ट जिक्र किया था। इसके ठीक विपरीत कांग्रेसी सूत्रों का दावा है कि एक नहीं, तीन पूर्व मुख्य आयुक्तों ने बहुसदस्यीय आयोग का विरोध किया है। स्वयं कांग्रेस समिति ने इसका सुझाव काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए दिया था। किंतु जांच-पड़ताल के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला गया कि आवश्यकता अतिरिक्त कर्मचारियों की है, अतिरिक्त आयुक्तों की नहीं।

धन-शक्ति का मुद्दा: विपक्ष के असंतोष का मुख्य कारण विधेयक में धन-बल और सत्ता-शक्ति पर नियंत्रण के प्रयासों का पूर्ण अभाव रहा है। विपक्ष ने चुनावों में काले धन के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम के लिए सरकारी आर्थिक सहायता की मांग की थी जिसे नकार दिया गया। इस मांग का विरोध करते हुए गाडगिल ने संसद में कहा था कि एक समय वे स्वयं इस मत के पक्षधर थे। किंतु गंभीर अध्ययन ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि यह निदान रोग से भी अधिक घातक है। उनके अनुसार न केवल खर्च बहुत बढ जायेगा, बल्कि अवांछित तत्व इसका दुरुपयोग भी करेंगे। गाडगिल का यह भी कहना है कि स्वयं जनता सरकार के जमाने में जेपी ने इसी मुद्दे पर तारकुंडे समिति बिठायी थी जिसने देश के मौजूदा माहौल में चुनावों में सरकारी सहायता को अव्यावहारिक बताया था। इसके विपरीत गुरुपदस्वामी का कहना है कि यह दलील अप्रासंगिक है, हम तो राजनीतिक पार्टियों को उनकी हैसियत और प्रभाव की दृष्टि से सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं। इस मद में जो ६८ करोड़ रुपए खर्च होने की उन्होंने (गाडगिल ने) बात की है, इतनी रकम तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विदेश यात्राओं पर खर्च हो जाती है।

विपक्ष का कहना है कि सरकारी आर्थिक सहायता की बात तो दरकिनार, श्रीमती गांधी के समय में तो चुनावों पर होनेवाले खर्च की सीमा को इस प्रावधान के साथ बढ़ा दिया गया था कि राजनीतिक पार्टियां किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए अपनी ओर से जो खर्च करेंगी उसे उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जायेगा। उसी के बाद चुनाव में अनाप-शनाप धन खर्च करने का प्रचलन शुरू हो गया। इस पर किसी प्रकार की रोकटोक की व्यवस्था मौजूदा विधेयक में न की जाने के कारण विपक्ष इसे मूलगामी कदम मानने को तैयार नहीं है।

विधेयक में धन-शक्ति पर तो ध्यान नहीं दिया गया, किंतु बल-शक्ति के बारे में अवश्य कुछ नयी व्यवस्थाएं की गयी हैं। कमजोर वर्गों को डरा-धमका कर मतदान से रोकने की आम प्रवृत्ति देखने को मिलती है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'माया' को बताया कि बिहार में मतदान के लिए आये लोगों के बीच हाथी-घोड़े दौड़ाकर उन्हें बिना वोट दिये घर लौटने के लिए विवश किया जाता है। यह रोग बिहार से शुरू होकर अनेक राज्यों में फैल गया था। पर मौजूदा विधेयक में मतदान में बाधा डालने या मतदान केंद्र

लालकृष्ण आडवाणी

आडवाणी के अनुसार, "आज १० साल बाद जब इस दिशा में निर्णय लिया, तो उसको सत्तापक्ष वाले ऐसा उछाल रहे हैं मानो देश पर बड़ी भारी अनुकंपा कर दी हो।" जयपाल रेड्डी का तो यहां तक कहना है, "वर्तमान चुनाव सुधार विधेयक का मुख्य लक्ष्य ऐसा भ्रम पैदा करना है जिससे लगे कि राजीव गांधी दलाली के आरोपों के दलदल में फंसे नहीं हैं।"

जयपाल रेड्डी

पर कब्जा करने को दंडनीय अपराध करार देकर सजा की अवधि और हर्जाने की राशि बढ़ा दी गयी है। इसके अतिरिक्त जन-प्रतिनिधित्व कानून १९५१ की एक धारा में संशोधन कर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का दायरा भी व्यापक कर दिया गया है।

विपक्ष के अनुसार कांग्रेस की आंखें तब खुलीं जब उसके इस हथकंडे का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों ने भी करना शुरू कर दिया—विशेषकर गैर इंका-शासित राज्यों में जहां कांग्रेस की दाल कम गल रही है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के प्रावधान को यद्यपि विपक्ष ने सराहा है, किंतु केवल ऐसी १७५ मशीनों के गिने-चुने स्थानों, संवेदनशील क्षेत्रों, में लगाये जाने को वह शंका की दृष्टि से देख रहा है। इसका अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के पास सुरक्षित रहना विपक्ष को बुरी तरह खटक रहा है।

वोटरों को पूरी तरह प्रभावित करनेवाला सर्वव्यापी मीडिया-तंत्र (टेलीविजन-रेडियो) भी सरकार के हाथों में बंधक है, ऐसा लगभग समूचा विपक्ष मानता है। ऐसी दशा में चुनाव में उसकी स्वतंत्र-निष्पक्ष भूमिका की संभावना कम होती है। इसी कारण उसने सुझाव दिया था कि कम-से-कम चुनावों के दौरान मीडिया चुनाव आयोग के अधीन कर दिया जाये। विपक्ष के इस सुझाव को भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया।

चुनाव-सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा मतों का आनुपातिक आधार रहा है। कांग्रेस ३०-४० प्रतिशत वोट पाकर भी अधिकाधिक सीटें हासिल कर लेती है। इसलिए मधु दंडवते ने प्रस्ताव रखा था कि कम-से-कम ५० प्रतिशत सीटें समानुपातिक आधार पर और सूची के तहत सुनिश्चित की जायें। तात्पर्य यह कि जिस पार्टी के कुल मतदान में जितने प्रतिशत वोट मिलें, उसी के आधार पर उसे सीटें भी हासिल हों। उन्होंने इस सिलसिले में पश्चिम जर्मनी का उदाहरण दिया, किंतु कांग्रेस ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। गाडगिल के अनुसार इसका पालन करनेवाले देश भी इससे अब पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि न तो यह व्यावहारिक है और न इससे सही प्रतिनिधित्व का ज्ञान होता है।

'नहीं' से बुरा नहीं : अब प्रश्न उठता है कि यह चुनाव विधेयक कितना सुधार करेगा ? विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग स्वयं किये गये सुधारों से कतई संतुष्ट नहीं। लगभग ६ महीने पहले भेजी गयी उसकी तमाम सिफारिशों को प्रस्तुत विधेयक में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है—विशेषकर उन सिफारिशों को जो सांगठनिक चुनावों, न्यूनतम चुनाव खर्च और अवांछनीय उम्मीदवारों की रोकथाम की व्यवस्था से संबंधित थीं। आयोग के एक सूत्र ने कहा, "सरकार के लिए उन्हें न मानना कोई अस्वाभाविक या आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस में तो वर्षों से सांगठनिक चुनाव हुए ही नहीं हैं। खर्च को बेलगाम करने का काम भी कांग्रेस ने ही श्रीमती गांधी के चुनाव-विवाद के उपरांत ही किया है।"'

विपक्ष ने जब इसे आधा-अधूरा और सतही कदम करार दिया, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसे विपक्ष का दृष्टिदोष ठहराया। कानून मंत्री बी० शंकरानंद तो मुद्दे की व्यापकता और क्लिष्टता की दुहाई के साथ यही दलीलें पेश करते रहे कि इतने विशाल और समस्याओं-भरे देश में चुनाव-सुधार जैसा काम एक झटके में करना असंभव है, विशेषकर धन-शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। जवाब में जयपाल रेड्डी का कहना है कि इस दिशा में कम-से-कम नेकनीयती का परिचय तो दिया ही जा सकता था जो नहीं दिया गया, क्योंकि सरकार इस रोग से निदान चाहती ही नहीं।

विधेयक ने सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न सरकार की नीयत पर ही लगाया है। सैफुद्दीन चौधरी को यदि इसमें निहित प्रावधानों के दुरुपयोग की शंका घेरे है, तो मधु दंडवते को यह चिंता कि सत्ता-दल शायद इसे कानून का स्वरूप धारण ही न करने दे। मतदाताओं की आयु २१ से १८ वर्ष करने वाले सर्वस्वीकृत ६२वें संविधान संशोधन पर 'माया' से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनके मन में सरकारी नीयत के प्रति शंका इसलिए उभरी है कि वह एकाएक इसे ५० प्रतिशत राज्य विधानसभाओं से पारित कराने की बात करने लगी है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देनेवाली धारा ३६८ में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई विधेयक दो-तिहाई मतों से संसद में पारित हो, तो उसे केवल राष्ट्रपति की सहमति ही चाहिए। इसी धारा में उन विषयों की भी सूची है जिन पर संशोधन के लिए ५० प्रतिशत राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है। इसी सूची में धारा ३२६ है जिसके तहत मतदाताओं की आयु घटायी जा सकती है। फिर सरकार इस संशोधन को राज्य विधानसभाओं के पास क्यों भेजना चाहती है ?

खामोश इबारतें: चुनाव आयोग का दफ्तर

> **चुनाव सुधार की वास्तविकता पहाड़ खोदने कर चुहिया मिलने की ही वास्तविकता है। सुधार से कहीं अधिक मंशा राजनीतिक लाभ उठाने का ही रहा है। आरोपों के कीचड़ में सनी राजीव सरकार के लिए लीपापोती द्वारा 'मुखौटा सुधार' उतना ही आवश्यक रहा है जितना विश्वसनीयता की पुनः स्थापना के लिए कम-से-कम कुछ वायदों को अमली जामा पहनाने का दिखावा, वह भी ऐसा जो दिखे अधिक पर वास्तविकता कुछ और ही हो।**

जयपाल रेड्डी के अनुसार सारा खेल समय नष्ट करने का बहाना है। नये मतदाताओं की भावी भूमिका से आशंकित सरकार अधिकाधिक ढिलाई और देरी कर उन्हें मताधिकार से वंचित भी करा सकती है। ज्ञात रहे कि विधानसभाओं द्वारा पारित होने के बाद ही चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा। इसमें कम-से-कम ५-६ महीने लगेंगे। समस्त कार्यवाही पूरी न होने की स्थिति में सरकार युवा वर्ग की ओर अपनी संवेदना का ढिंढोरा पीट श्रेय भी लूट लेगी और संभावित हानि से भी बच निकलेगी, अर्थात सांप भी मर जायेगा और लाठी भी न टूटेगी।

रेड्डी कहते हैं, "सरकार की इसी चाल को समझते हुए विपक्ष ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त चयन समिति को भेजने का वह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जो वह साधारणतया करता है। हमें डर था कि इसके बहाने सरकार कहीं अपने वायदे से पीछे न हट जाये।"

चुनाव सुधार की वास्तविकता पहाड़ खोदने पर चुहिया मिलने की ही वास्तविकता है। सुधार से कहीं अधिक मंशा राजनीतिक लाभ उठाने का ही रहा है। आरोपों के कीचड़ में सनी राजीव सरकार के लिए लीपापोती द्वारा 'मुखौटा सुधार' उतना ही आवश्यक रहा है जितना विश्वसनीयता की पुनः स्थापना के लिए कम-से-कम कुछ वायदों को अमली जामा पहनाने का दिखावा, वह भी ऐसा जो दिखे अधिक पर वास्तविकता कुछ और ही हो। प्रसिद्ध राजनीतिक पर्यवेक्षक निहाल सिंह के अनुसार वर्तमान माहौल में (विशेषकर तब जब सरकार के सामने सबसे कठिन चुनाव मुंह बाये खड़ा हो) इससे अधिक सुधार की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। कारण, संगीन मुकाबले के ऐन पहले सरकार अपनी लाभप्रद स्थिति कभी खोना नहीं चाहेगी।

अंततः कौन क्या खोयेगा और क्या पायेगा यह तो समय ही बतायेगा और विधेयक का उपयोग-दुरुपयोग भी। किंतु फिलहाल कांग्रेस का दावा है कि उसने मतदाता-आयु घटाने में पहल कर विपक्ष के हाथों से बाजी और मुद्दा भी हथिया लिया है। अतः चुनाव सुधार का यह कदम कितना भी ठिठका आधा-अधूरा क्यों न हो—किंतु 'नहीं' से बुरा नहीं।

—रंजना कक्कड़

भारत में सबसे ज्यादा बिकनेवाली हिन्दी पत्रिका

मनोहर कहानियाँ

रहस्य-रोमांच
विशेषांक
भारत में सबसे ज्यादा बिकनेवाली हिन्दी पत्रिका
मनोहर कहानियाँ

मनोहर कहानियां के रहस्य-रोमांच विशेषांक में वास्तविक जीवन के अनबूझे रहस्यों के रोमांचक क्षणों को सुप्रसिद्ध तथा जाने-माने कहानीकारों द्वारा अत्यन्त ही दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है

*मनोहर कहानियां का
एक अपूर्व संग्रहणीय अंक*

**तंत्र-मंत्र, भूत-प्रेत,
परलोकजीवी आत्माओं की रहस्यमय
गतिविधियों तथा ऐसे ही अन्य
अनेक विषयों पर आधारित सत्यकथायें
तथा लघु कथाओं से भरपूर**

मार्च '८९

चीन-पाक से समझौते के लिए

राजीव झुकेंगे या झुकायेंगे ?

३४ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा जहां अभूतपूर्व, महत्वपूर्ण और साहसी रही, वहीं चौमुख चर्चा और विवाद का मुद्दा भी बनी है। इसका सबसे बड़ा कारण १९६२ में चीन का भारत पर आक्रमण और हजारों मील भारतीय सीमा क्षेत्र पर कब्जे का मुद्दा है। पाकिस्तान से भी भारत के रिश्तों की स्थिति कोई विशेष भिन्न नहीं है। भारत-विभाजन के दौरान हुआ सबसे बड़ा सांप्रदायिक नरसंहार और उसके बाद के दो भीषण युद्धों ने नफरत की जो दीवार खड़ी की थी, उसे गिराना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं था। प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किन परिस्थितियों में इन पड़ोसी देशों के साथ टूटे धागों को पुनः जोड़ने का प्रयास शुरू किया। उनकी अनिवार्यताएं, विवशताएं और मूल उद्देश्य क्या था ? क्या सचमुच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय सफलता व उपलब्धियों से अपनी राष्ट्रीय विफलताओं और आरोपों की कालिमा को धोना चाहते हैं अथवा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मान कर वह ऐसा साहसिक और जोखिम भरा कदम उठाने को तत्पर हुए ? राजीव गांधी ने चीन के संबंध में जो नीति अपनायी है, क्या इसका कारण यह है कि उनके हाथ बंधे थे ? प्रश्न यह भी है कि अंततः ये यात्राएं घाटे का सौदा साबित होंगी या मुनाफे का ?

आपसी विश्वास:
पाकिस्तान के साथ समझौते पर
दस्तखत करते हुए
मेनन और हुमायूं खान

गर्मजोशी:
देंग और राजीव

> **आडवाणी ने कहा, "इस निष्फल और पूर्णतया शुष्क यात्रा का एकमात्र मकसद कदाचित यह था कि एक नये देश का सैर-सपाटा कर आयें। राजीव गांधी ने तो भारतीय संसद के १९६२ के उस प्रस्ताव को भी पूर्णतया नजर अंदाज किया जिसमें चीन अधिकृत अपनी एक-एक इंच भूमि वापस लेने का संकल्प किया गया था।"**

प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बहुप्रचारित चीन और पाक यात्राओं के संबंध में सबसे विशिष्ट और विचित्र बात यही है कि इतना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने से पूर्व प्रधानमंत्री, सरकार अथवा उनकी पार्टी ने न तो भारतीय जनमानस की नब्ज टटोली और न उसके बीच संबंधित मुद्दे साफ किये। खासकर इसलिए कि यह पहल काफी वर्षों के बाद हो रही थी। दोनों देशों से भारत के युद्ध हो चुके हैं और पिछले ३४ वर्षों में न तो कोई भारतीय प्रधानमंत्री चीन गया है व न पिछले २७ वर्षों में पाकिस्तान गया है। ऐसे में देशव्यापी माहौल बनाने का राई-रत्ती प्रयास और परवाह न करना भारतीय जनतंत्र के उस खोखलेपन को उजागर करता है, जहां सरकार जनता को अपने विश्वास में लेना आवश्यक नहीं समझती।

बात विदेश यात्रा पर जाने तक ही सीमित नहीं। वापसी के बाद भी यथास्थिति बरकरार है। प्रधानमंत्री अथवा उनकी सरकार ने इन यात्राओं और उसकी 'उपलब्धियों' के संबंध में देशवासियों को किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी देने का कोई प्रयास नहीं किया है। न ही इस बात को तरजीह दी कि जनता के मन में व्याप्त उत्सुकता, आशंका और चिंता का निवारण करे। उसको विश्वास दिलाये कि इन दो पड़ोसी देशों की अपनी यात्राओं में प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, जिससे इस महान देश के गौरव को कोई धक्का लगे या उसके हितों को क्षति पहुंचे। ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री को पूरे देश का दौरा करने की जरूरत नहीं थी। जनता से रूबरू होने के लिए उनके पास रेडियो-दूरदर्शन के देशव्यापी जाल का माध्यम भी है और अनुभव भी।

"उपलब्धि कुछ हुई हो तभी तो उसका जिक्र प्रधानमंत्री कर सकेंगे," भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने 'माया' से इस सिलसिले में बातचीत करते हुए कहा। आडवाणी आगे बोले, "इस निष्फल और पूर्णतया शुष्क यात्रा का एकमात्र मकसद कदाचित यह था कि एक नये देश का सैर-सपाटा कर आयें। राजीव गांधी ने तो भारतीय संसद के १९६२ के उस प्रस्ताव को भी पूर्णतया नजरअंदाज किया, जिसमें चीन अधिकृत अपनी एक-एक इंच भूमि वापस लेने का संकल्प किया गया था। राजीव गांधी यदि और कुछ नहीं तो यह तो चीन को बताकर आते कि वे अपनी संसद के उक्त प्रस्ताव से बंधे हुए हैं।"

आडवाणी इसे भले ही निष्फल और शुष्क यात्रा क्यों न मानें, किंतु अधिकांश लोग इसे एक व्यावहारिक और साहसिक कदम करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ चीन की यात्रा पर गये प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने 'माया' को बताया कि स्थिति कितनी जटिल थी, यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चीन के वयोवृद्ध, चोटी के नेता केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष देंग जियाओपिंग की मुलाकात के पहले के क्षणों से स्पष्टतया उजागर था। उक्त सूत्र के अनुसार माहौल तनाव और अनिश्चितता से परिपूर्ण था। होता भी क्यों नहीं? इस पूरी यात्रा का दारोमदार देंग की इस मुलाकात द्वारा व्यक्त संकेतों पर निर्भर जो था। कदाचित यही कारण है कि बड़ी गर्मजोशी के साथ देंग राजीव गांधी का हाथ लगातार तीन मिनट तक पकड़े कहते रहे कि "स्वागत है नौजवान दोस्त। आपकी यात्रा से हमें विश्वास है रिश्ते दोस्ताना बनेंगे। दोनों देश दोस्त बनेंगे, लोग दोस्त बनेंगे"... तो राजीव गांधी अवाक रह गये। उनके लंबे मौन को गरजदार आवाज में तोड़ते हुए देंग ने आगे कहा, "क्या आप सहमत हैं मुझसे?" तो उन्होंने हामी भरने में ही खैर समझी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि उस मौके पर स्व० प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होतीं, तो नजारा ही कुछ और होता। वे निश्चय

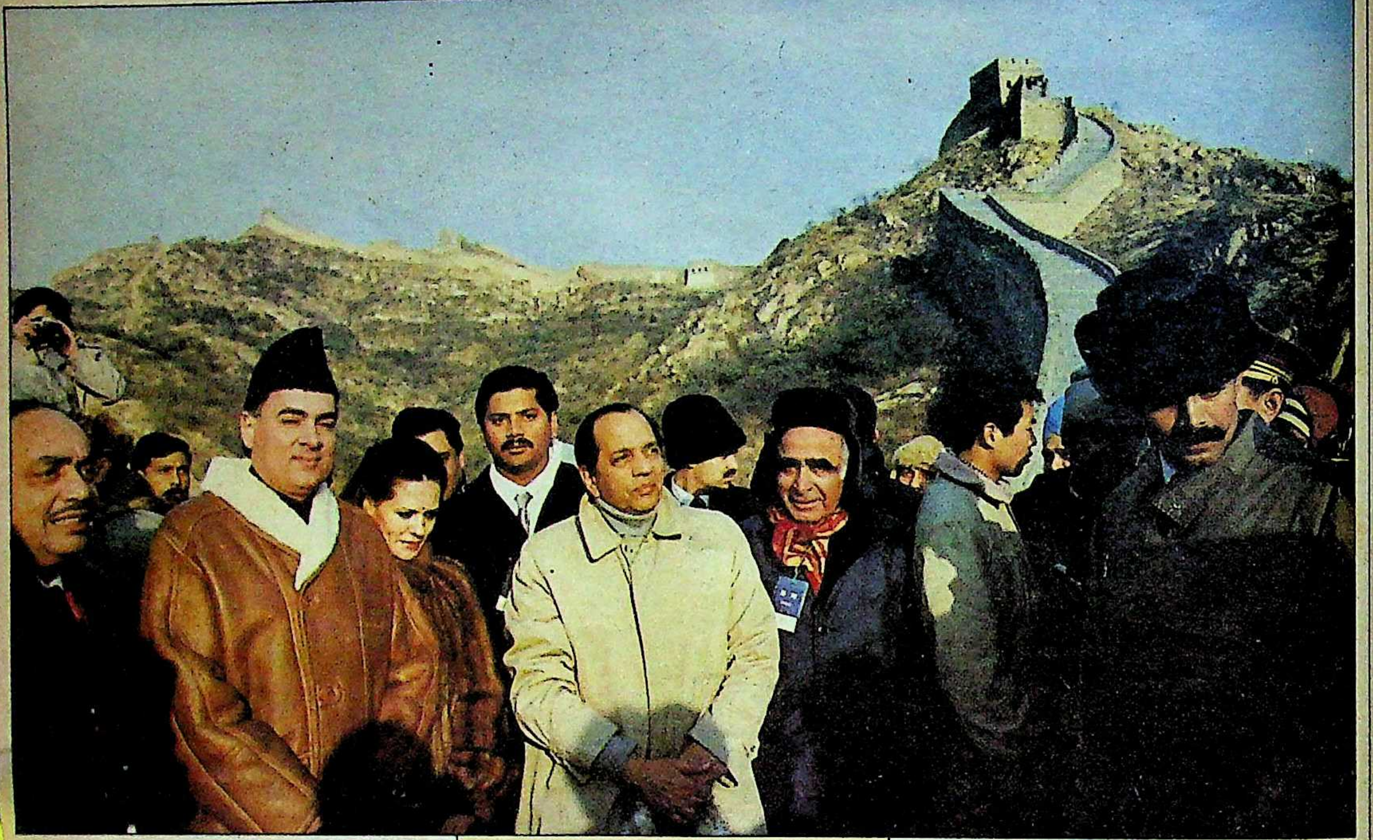

दुश्मनी की दीवार तोड़ने की पहल : राजीव और सोनिया शिष्ट मंडल के साथ

ही यही जवाब देतीं, "आप ठीक ही कहते हैं। हमें इस पर अवश्य गौर करना चाहिए।"

राजीव गांधी के हतप्रभ होने की एक वजह जहां उनके आलोचक उनका अल्पानुभवी होना मानते हैं, वही विषम राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को भी मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दिनोदिन घटती साख प्रधानमंत्री को किसी नयी पहल के लिए निरंतर व्यग्र-विकल करती रही है। खासकर तब, जब आम चुनावों के लिए महज एक वर्ष और फौरी चुनावों की सूरत में चंद महीने ही बाकी हैं। प्रख्यात राजनीतिक पर्यवेक्षक भवानी सेन गुप्त का भी यही मानना है कि राजीव गांधी ने इस पहल से यथास्थिति और आरोपों के दलदल में उभरी निष्क्रियता की अपनी छवि को तोड़ने का भी प्रयास किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर दिनोदिन घटती साख प्रधानमंत्री को किसी नयी पहल के लिए निरंतर व्यग्र-विकल करती रही है। खासकर तब, जब आम चुनावों के लिए महज एक वर्ष और फौरी चुनावों की सूरत में चंद महीने ही बाकी हैं।

विपक्षियों के आरोप : अनेक विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अपनी राष्ट्रीय विफलताओं को ढंकने-मूंदने और धूमिल छवि को मांजने-चमकाने की भावना से प्रेरित होकर ही राजीव गांधी ने चीन की यात्रा का ताबड़तोड़ फैसला किया। वह भी एक पुराने और धूल जमे दावतनामे पर। जब इसकी चर्चा प्रधानमंत्री के एक निकट सहयोगी से चली, तो उन्होंने अपना नाम न लेने के अनुरोध सहित बताया, "किसी भी प्रधानमंत्री के लिए चीन यात्रा का निर्णय कठिन ही नही, जोखिम भरा भी रहा है। कारण दोनों देशों में इसकी क्रिया-प्रतिक्रिया क्या होगी, यह कहा नहीं जा सकता। पूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अनुभव अभी कोई भूला नहीं है। उनकी ऐन चीन यात्रा के दौरान ही चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया था। नतीजतन वाजपेयी अपनी यात्रा अधूरी छोड़ स्वदेश वापस लौटने को विवश हो गये थे। इसलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा उठाया गया यह कदम उनके साहस और राजनीतिक सूझबूझ का नमूना है।"

उक्त सूत्र के अनुसार चीन से चल रही आधिकारिक स्तर की बातचीत एक ऐसे पड़ाव व ठहराव की स्थिति में पहुंच गयी थी, जहां सही व समुचित राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना गाड़ी आगे बढ़नी मुश्किल थी। रही दावतनामा बासी होने की बात, तो यह सच है कि यह श्रीमती गांधी के शासनकाल में आया था। किंतु उनके मृत्योपरांत अंतिम संस्कार में भाग लेने आये चीनी उपराष्ट्रपति ने इसका नवीकरण करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी से चीन यात्रा का अनुरोध किया था। अक्तूबर '८५ में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष चाओ ज यांग की न्यूयार्क (अमरीका) में बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से भेंट हुई थी, जिसमें चीन यात्रा का निमंत्रण पुनः दोहराया गया था।

फैसला ताबड़तोड़ लिया गया, आधिकारिक रूप से यह भी नहीं स्वीकारा जाता। जानकार सूत्रों का कहना है कि बातचीत की अंतिम बैठक के दौरान भारत को यह निश्चित संकेत प्राप्त हुए कि चीनी आक्रामक रवैये में मूलगामी परिवर्तन आ गया था और स्वयं चीन पुराने द्वेष, वैमनस्य भुलाकर मित्रता और सहयोग का आकांक्षी हो गया था। एक वरिष्ठ राजनयिक के अनुसार, "इसी तथ्य को मद्देनजर रख प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमें अपने संबंधों को पुनः जोड़ना और मतिशील करना चाहिए।" गत एक वर्ष से हमने न केवल एक दूसरे से निकट संपर्क बनाये रखा, बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार का आपसी तनाव न पैदा हो।

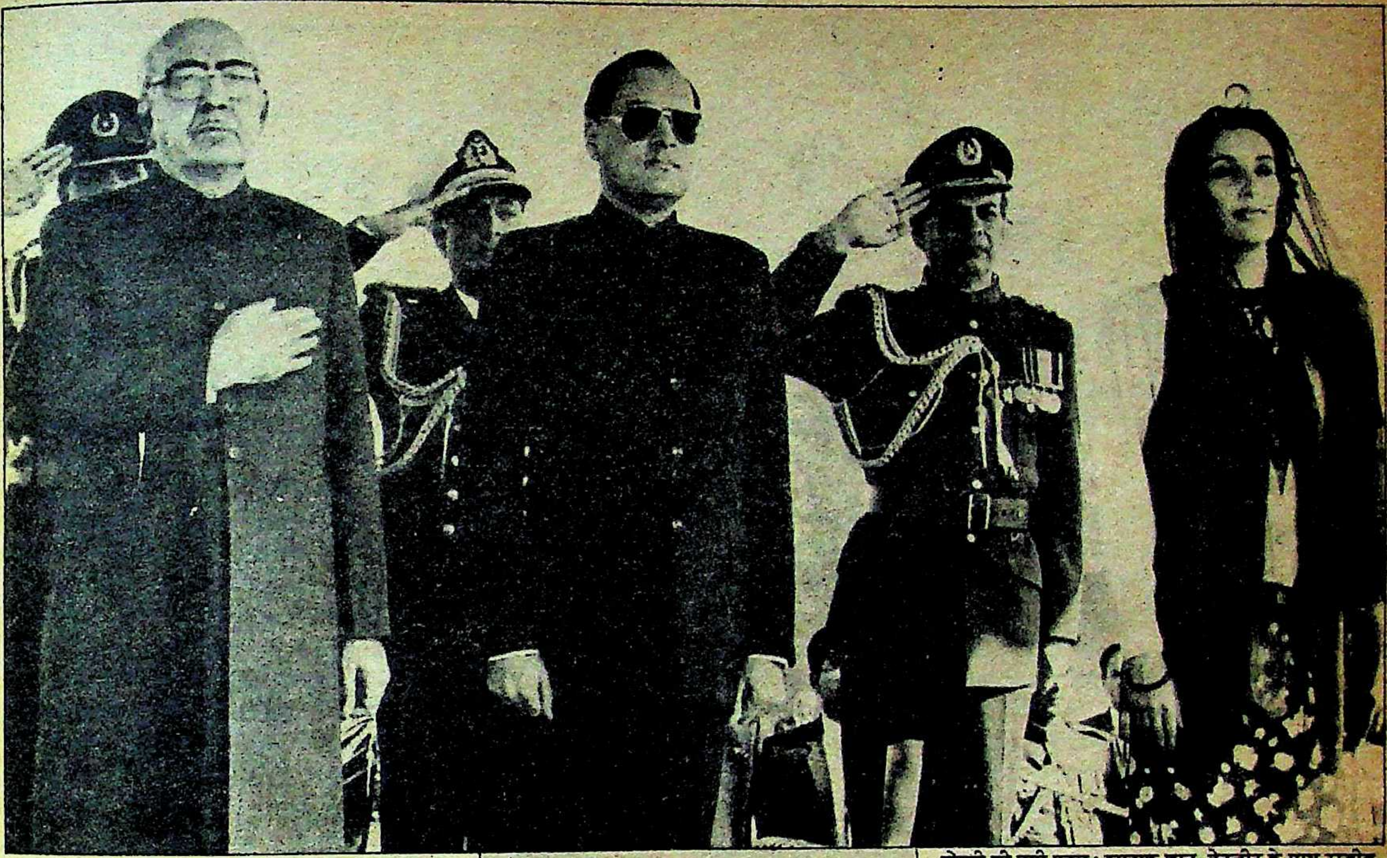

दोस्ती की नयी पहल : इसहाक खान, बेनजीर के साथ राजीव गांधी

रूसी दबाव : चीनी मामलों के विशेषज्ञ और चीन के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क रखने वाले बहुचर्चित जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी इस पहल के पीछे 'चीन से अधिक सोवियत संघ का हाथ' देखते हैं। 'माया' से विस्तृत बातचीत में स्वामी ने कहा, "मैं भारत-चीन मैत्री का प्रबल समर्थक रहा हूं। यदि हमारे प्रधानमंत्री सचमुच अपनी पहल से वहां (चीन) गये होते, तो मुझसे अधिक खुश कोई और न होता। किंतु सोवियत संघ द्वारा धकियाकर भेजे जाने को मैं भारत की ८० करोड़ जनता का सीधे-सीधे अपमान समझता हूं।" उनके अनुसार सोवियत संघ ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से धक्के लगाये। राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने तो सीधे उन्हें (राजीव गांधी को) चीन के सामने आत्मसमर्पण करके मैत्री करने को कहा। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारी व प्रधानमंत्री के जाने-माने सोवियत समर्थक सलाहकारों—गोपी अरोड़ा और रनेन सेन को इस्तेमाल किया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण चीन यात्रा में विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय को कोई महती भूमिका नहीं निभाने दी गयी। इस संबंध में चीन जा कर जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि तैयार की गयी, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और विशेष कर उसके इन्हीं दो (अरोड़ा व सेन) सलाहकारों ने महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभायी।

भारत-पाकिस्तान के संबंधों के सुधार में राजीव गांधी की अपेक्षा बेनजीर भुट्टो के हाथ कहीं अधिक बंधे हुए हैं। भावी संबंध कितने सुधरेंगे यह इस पर निर्भर करेगा कि विषम परिस्थितियों से जूझती बेनजीर भुट्टो कब तक अपना अस्तित्व बचा पाती हैं और अपनी स्थिति कितनी सुदृढ़ कर सकेंगी।

पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री व सोवियत संघ में भारत के राजदूत रह चुके जाने-माने राजनीतिक पर्यवेक्षक इंद्र कुमार गुजराल का मानना है कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के संबंध में सोवियत संघ का कोई प्रभाव या दबाव नहीं रहा है। उनके अनुसार यदि ऐसा होता भी, तो वह स्वीकार्य न होता। मिसाल के तौर पर गुजराल ने 'माया' को बताया कि जिन दिनों वे स्वयं सोवियत संघ के राजदूत थे और चीन से संबंध सुधारने के लिए कुछ हिचकिचाहट भरे कदम उठाये जा रहे थे, तो सोवियत संघ ने हमें रोकने-टोकने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हमने उनके हर प्रयास को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि अपनी मुहिम में लगे रहे। गुजराल यह अवश्य स्वीकारते हैं कि राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने भारत यात्रा के दौरान एक ओर तो चीन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए सलाह और प्रोत्साहन दिया था और दूसरी ओर यह संकेत कि चीन और भारत के मध्य भावी तनावों की स्थिति में भारत को सोवियत संघ के समर्थन और सहयोग की विशेष अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अकलमंद के लिए इतना इशारा काफी था।

सोवियत संघ के इस बदले रुख के पीछे प्रमुख कारण यह था कि उसके चीन से संबंध सुधरने की संभावना दिनोदिन बेहतर होने लगी है। इस बदलते समीकरण के कारण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में भी आधारभूत परिवर्तन होना शुरू हो गया है। इस नये परिदृश्य को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि जब सोवियत संघ और चीन के संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई थी, तो सोवियत संघ ने भारत को अपने साथ लिया था। चीन से भारत की नाराजगी का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वह भारत को सोवियत संघ का पुछलग्गू मानता था। अतः भारत के लिए चीन से संबंध बनाना और सहयोग का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था।

तीव्र गति से परिवर्तित अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी इन नये रिश्तों की दागबेल डालने के लिए अपरिहार्य बन गया था। वर्षों जंग के मैदान में

भारत-चीन के बीच झगड़े की जड़

हिंदी-चीनी भाई-भाई का दुःस्वप्न : नेहरू और चाउ-एन-लाई

अक्तूबर १९८६ में जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सुमदोरांग घाटी में घुसपैठ की, तो दूसरे भारत-चीन युद्ध की आशंका होने लगी थी। इस घुसपैठ का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और यह दौर कई महीनों तक चला। बाद में चीनी फौज वापस हो गयी, लेकिन चीन ने इस इलाके पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। इस पृष्ठभूमि में जब राजीव गांधी ने अपनी पहल पर चीन की यात्रा की, तो राजनीतिक पंडितों ने तुरंत भविष्यवाणी कर दी कि इस यात्रा से कोई भी उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है।

जिस गर्मजोशी और सद्भाव वाले माहौल में भारतीय दल का चीनियों ने स्वागत किया, उसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण बताया। लेकिन सीमा-विवाद पर स्थिति वैसी ही बनी रही और इसे एक संयुक्त कार्य दल को सौंप दिया गया, जिसे अपना काम पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गयी।

निखिल चक्रवर्ती जैसे राजनीतिक विश्लेषण करने वालों ने इस यात्रा को मिले प्रचार को प्रधानमंत्री कार्यालय की एक बड़ी उपलब्धि बताया। लेकिन कई अन्य राजनीतिक पंडितों ने तिब्बत के बारे में भारत सरकार की नयी घोषणा को सीमा-विवाद सुलझाने के लिए उचित माहौल बनाने के लिए 'तिब्बत की बलि' देना करार दिया।

१९४९ में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद से भारत और चीन की सीमा तीन इलाकों में लगने लगी—पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख), मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश) तथा पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश)। अक्तूबर १९८७ में चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में सिंगकियांग-तिब्बत राष्ट्रीय मार्ग खोला। यह रास्ता अक्साई चिन के भारतीय इलाके से होकर गुजरता है। जब यह मार्ग खुला, तो लद्दाख क्षेत्र में १४५०० वर्ग मील भारतीय इलाके पर चीन ने नाजायज कब्जा जमा लिया था। पूर्वी क्षेत्र में चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश का ३३०० वर्ग मील क्षेत्र उसका है। पूर्वी क्षेत्र में भारत और तिब्बत (जो अभी चीन के नियंत्रण में है) के इलाके को मैकमोहन रेखा अलग करती है और इसी रेखा को लेकर विवाद है। यह सीमा अंग्रेजी शासन वाले भारत, चीन और तिब्बत के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते से तय हुई थी। लेकिन इस समझौता बैठक के दो दिन बाद ही चीन सरकार ने इस सीमा-रेखा को मानने से इनकार कर दिया था।

यही रेखा अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले 'नेफा' कहा जाता था, की उत्तरी सीमा को तय करती है और चीन करीब-करीब इस पूरे इलाके पर ही अपना दावा करता है।

पश्चिमी क्षेत्र में उपनिवेश काल के नक्शों में सीमा को कराकोरम पहाड़ी के शिखर से दिखाया गया है और ऐसे में अक्साई चिन उस पार आता है। लेकिन भारत ने जो नक्शा छापा, उसमें ३८४०० वर्ग किमी के इस पूरे इलाके को अपना हिस्सा बताया गया। चीन इस इलाके की १४५०० वर्ग मील जमीन पर अपना दावा करता है। इसके बावजूद शांतिपूर्ण सहअस्तित्ववाली संधि, पंचशील पर १९५४ में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने दस्तखत किये।

लेकिन १९५९ में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बतियों के विद्रोह और दलाईलामा के भारत में राजनीतिक शरण लेने के साथ ही चीन ने आरोप लगाया कि भारत, चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करके पंचशील संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। फिर अक्साई चिन सीमा में छिटपुट झड़पों के बाद चीन ने पूर्व क्षेत्र में अक्तूबर १९६२ में भारतीय सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। महीने भर बाद बेजिंग ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की। चीन ने अपनी सेनाओं को मैकमोहन रेखा के अंदर बुला लिया, पर लद्दाख क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ और यहां झड़पें चलती रहीं।

इस युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध बहुत ही बिगड़े रहे और चीन ने १९६५ और १९७१ के भारत-पाक युद्धों में भारत को ही हमलावर करार दिया।

भारत-चीन संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया १९७६ में शुरू हुई, जब दोनों ने कई मामलों में सहयोग करने का फैसला किया। ऐसा होने से किसी भी देश ने अपने रवैये में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक-दूसरे के हितों को मानने की दिशा में ही प्रगति हुई। जनता शासन काल (१९७७-८०) में इस दिशा में और प्रगति हुई और भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गये और वहां के विदेशमंत्री हुआंग हुआ भारत आये।

जून १९८० में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नये लौह पुरुष और अध्यक्ष देंग जियाओ पिंग द्वारा सीमा समस्या सुलझाने का एकमुश्त प्रस्ताव दिये जाने के बाद दिसंबर १९८१ से दोनों देशों ने इस बारे में औपचारिक बातचीत शुरू की। लेकिन इस प्रस्ताव के तहत बात आगे बढ़ नहीं पायी, क्योंकि इससे किसी बदलाव की जगह यथास्थिति को ही मंजूरी मिलनी थी। आधिकारिक स्तर की बातचीत कुछ और दौर तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

बातचीत आगे न बढ़ने का एक बड़ा कारण था चीन द्वारा जारी नक्शों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग दिखाना। पंजाब और पूर्वोत्तर के आतंकवादियों के पास एके-४७ चीनी राइफलों के पहुंच जाने पर भी संसद में कई बार चिंता प्रकट की गयी। ■

रूबरू देश सुलह-समझौते के लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अमरीका और सोवियत संघ संधि और सहयोग के लिए मिलें-बैठेंगे, ईरान और इराक के बीच वर्षों ठना घमासान युद्ध खतम हो जायेगा, पीएलओ आतंकवाद का रास्ता छोड़कर आज इस्राइल से बातचीत को तैयार हो जायेगा, अफगानिस्तान में वर्षों तैनात सोवियत सेना की वापसी होगी आदि। ऐसी स्थिति में भारत के लिए चीन से अपने विवादों के हल के लिए पेशकदमी न करना, किसी प्रकार भी बुद्धिमत्ता का कदम न कहा जाता।

राजीव गांधी की चीन-पाक यात्राओं से देश को अंततः कितना लाभ होगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा। राजीव गांधी को राजनीतिक लाभ पहुंचा है, चाहे वह वामपंथियों के समर्थन का हो अथवा मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का, यह भी कोई विशेष आलोचना या चिंता का मुद्दा नहीं। विश्व के सभी नेता चाहे वे अमरीका के रिचर्ड निक्सन हों, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर हों या भारत की इंदिरा गांधी-प्रत्येक ने समय-समय पर अपनी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहलकदमियों द्वारा लाभ उठाने का सदैव प्रयास किया है।

राजीव की मजबूरियां: राजनीतिक अनिवार्यताओं के अतिरिक्त आर्थिक दबाव भी कुछ कम नहीं रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे कुल आयात का लगभग साढ़े १८ प्रतिशत व्यय प्रतिरक्षा पर होता है और वह भी अधिकांशतः विदेशी मुद्रा में। विदेशी कर्जों का बढ़ता बोझ जगजाहिर है। यदि हम इन खर्चों पर रोक नहीं लगायेंगे, तो पहला खतरा यह है कि पानी सिर से गुजर जायेगा। दूसरे, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट और मंदी के चलते भविष्य में विदेशी कर्जों की प्राप्ति भी दिनोदिन संदेहजनक होती जा रही है। आवश्यक आयातों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भारत को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सैन्य खर्चों में कटौती न करने का सीधा प्रभाव हमारी पंचवर्षीय योजनाओं और राष्ट्रीय निर्माण के अन्य आवश्यक पहलुओं पर पड़ेगा।

मित्रता का हाथ बढ़ाने की विवशता केवल भारत की अपनी ही नहीं थी। चीन के बदले रवैये के पीछे भी कुछ विवशताएं रही हैं। आर्थिक संकट चीन में भी गंभीर हैं। १९८८ में मुद्रा स्फीति की दर २६ फीसदी से भी ऊपर पहुंच गयी। भयंकर सूखे के कारण कृषि की हालत भी असंतोषजनक है।

भारत-पाक विवादों की श्रृंखला

१९४७ में एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का उदय 'हिंदू-विरोध' के कारण ही हुआ। उसके बाद से भी विरोध जारी है, लेकिन अब इसका स्वरूप 'भारत-विरोध' हो गया है। एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान अपना अस्तित्व भारत के साथ मतभेद बनाये रखकर और नये मतभेद पैदा करके ही बनाये रख सकता है और इसी से उसका औचित्य भी साबित होता है। लेकिन आज भी भारत के अधिकांश लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण बना और एक ऐतिहासिक राष्ट्र के रूप में इसका वजूद है ही नहीं। दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों के बीच विवाद की पृष्ठभूमि यही है।

भारत और पाकिस्तान के कड़वे संबंधों के लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा कश्मीर का है। १९४८ में पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुस गयी और उसने इसके आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। कश्मीर सीमा पर हुई झड़पों के बाद १९६५ में दूसरा भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तान की मांग है कि उसे पूरा कश्मीर दे दिया जाये।

दूसरी ओर भारत अभी भी अपने नक्शों में पूरे कश्मीर को अपना अंग बताता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान द्वारा इस मसले को उठाये जाने को वह शिमला समझौते का उल्लघंन मानता है। यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। समझौते में कहा गया था कि इस मसले को आपसी बातचीत से ही सुलझाया जायेगा और इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से नहीं उठाया जायेगा।

यह स्पष्ट है कि अभी भी पाकिस्तान भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है और यहां होने वाले हिंदू-मुस्लिम दंगों को उछालने से बाज नहीं आता। भारत इसे अपनी सार्वभौमिकता का उल्लघंन मानता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत 'मुस्लिम पाकिस्तान के सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्तित्व' को बर्दाश्त नहीं करता। १९७१ में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद यह डर और बढ़ गया है।

पंजाब में आतंकवाद के उदय के साथ ही भारत सरकार पाकिस्तान पर सप्रमाण यह आरोप लगाती रही है कि वह आतंकवादियों को मदद और बढ़ावा दे रहा है। भारत का दावा है कि पंजाब के आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविर लगाये गये हैं और इस बात के उसके पास पक्के प्रमाण हैं। उधर पाकिस्तान का आरोप है कि सिंध में हो रहे उत्पात के पीछे भारत का हाथ है।

इस विवाद के अलावा दोनों देश एक-दूसरे के यहां एटम बम बनने के अंदेशे से भी परेशान रहे हैं। इस संदेह को दूर करने के लिए स्व० जिया उल हक ने एक-दूसरे के एटमी ठिकानों के निरिक्षण, दक्षिण एशिया को एटमी हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित करने और परमाणु अप्रसार संधि कर लेने का प्रस्ताव दिया था। भारत ने इस प्रस्ताव के बारे में तब ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन दिसंबर १९८८ में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाक प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने एक-दूसरे के एटमी ठिकानों पर हमला न करने की संधि पर हस्ताक्षर किये।

विवादों की श्रृंखला में नया मुद्दा है सियाचिन का। दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कराकोरम पहाड़ी श्रृंखला के उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में है। २४००० फुट ऊंचाई होने के कारण यहां सामान्य जीवन संभव नहीं है। यहां स्पष्ट सीमा रेखा न होने के कारण ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। विभाजन के समय अंगरेजों ने यहां कोई स्पष्ट सीमा नहीं तय की। पाकिस्तान इसे 'आजाद कश्मीर' (अधिकृत कश्मीर) का हिस्सा मानता है, तो भारत इसे अपना इलाका। विवाद बना हुआ है और १९८४ के मध्य में भारत द्वारा यहां सैनिक अड्डा बनाये जाने के साथ ही शुरू हुई छिटपुट झड़पों का दौर अभी भी जारी है। १९८४ के बाद हुए सभी पाक हमलों को नाकाम कर देने के बाद निश्चित रूप से आज इस क्षेत्र में भारत बेहतर स्थिति में है।

लेकिन इन विवादों के रहते हुए भी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद दोनों देशों में संबंध सुधरने के लिए आशा का माहौल बना है और दोनों देश विवादों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। अब पहले जैसा नीयत पर संदेह नहीं रह गया है।

—पद्मा शास्त्री

यही नहीं राजनीतिक समीकरण के बदलते रुख ने भी चीन को भारत के प्रति नरमी से देखने को उन्मुख किया है। चीनियों को यकायक अहसास हुआ है कि माओवाद का न केवल विश्व दृष्टिकोण गलत था, बल्कि सातवें दशक में शुरू उसका अमरीकी समर्थक रुख भी निष्फल सिद्ध हुआ है। क्योंकि अमरीका से न तो उसे विशेष और अपेक्षित आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई और न तकनीकी। इस बीच इर्द-गिर्द फैले जापान की दिनोदिन उभरती शक्ति भी उसके लिए चिंता का कारण बन गयी है। सर्वोपरि विवशता गोर्बाचेव की शांति-सहयोग की पहलकदमी थी, जिसने न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अमरीका में तनाव शैथिल्य और परस्पर संबंधों का मार्ग प्रशस्त किया। सोवियत संघ और अमरीका में जारी शीतयुद्ध की समाप्ति से चीन के लिए इन दोनों महाशक्तियों को अलग-अलग तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना भी अब मुमकिन नहीं रह गया था।

अधिक लाभ किसको ? : प्रश्न यह उठता है कि जब दोनों ही देश अपनी-अपनी विवशताओं से आगे बढ़ने को उत्सुक थे, तो अधिक लाभ किसके खाते में गया। चीन को भली-भांति जानने वाले अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि चीन सौदेबाजी में माहिर है। उसका हर कदम नपातुला, सोचा-समझा और जांचा-परखा होता है। अपनी मनमानी करने-करवाने में उसकी महारत का कटु अनुभव भारत को ताजा है। भारतीय और चीनी नजरिए का फर्क छठे दशक में उभरे मानचित्रों के उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है। उल्लेखनीय है कि १९५४ के समझौते पर जब बातचीत जारी थी, तो उस समय चीन द्वारा जारी मानचित्रों ने पश्चिमी क्षेत्र का अक्साई चिन और पूर्वी क्षेत्र के अरुणाचल को तिब्बत का क्षेत्र दिखा दिया था। जब भारत ने इसका विरोध करते हुए चीन का ध्यान आकृष्ट किया, तो चीनियों ने यह समझा दिया कि ये मानचित्र क्विमिन तांग के पुराने मानचित्रों पर आधारित हैं और चीन उनको संशोधित नहीं कर सका है।

भारत ने इस मौखिक कथन पर ही विश्वास कर लिया। भारतीय मानचित्रों को चीनी मान्यता दिलाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। १९५४ के समझौते के समय इस पर अमल न करने का खमियाजा भारत को बाद में उठाना पड़ा। उसने संबंधित अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा करके आज तक अपना दावा बरकरार रखा है। चीन-भारत सीमा विवाद का श्रीगणेश यहीं से हुआ।

एक वरिष्ठ सैन्य पर्यवेक्षक के अनुसार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अक्साई चिन इलाके को लेकर जब विवाद बहुत बढ़ा, तो महज उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक और मोर्चा नेफा में खोल दिया। १९६२ का चीन-भारत युद्ध इसी का एक अंग था। दो मोर्चे खोल लेने का लाभ चीन को आज भी प्राप्त है। कारण इससे उसकी मोलतोल की हैसियत बढ़ गयी है।

दिनेश सिंह

सीमा की समस्या अभी भी बरकरार है। लेकिन व्यापार, वाणिज्य, तकनीक व संस्कृति का आदान-प्रदान आरंभ होगा।

मोलतोल और हैसियत चीनी कूटनीति का एक अभिन्न अंग है। सुब्रह्मण्यम स्वामी के अनुसार, "चीन सबसे पहले यह देखता है कि आप कितने पानी में हैं। उसी के अनुसार वह आपसे व्यवहार करता है और इज्जत देता है।" स्वामी के अनुसार उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से पूर्व हुई अपनी दो मुलाकातों में बड़ी स्पष्टता के साथ बतायी थी। इस संबंध में 'माया' को उन्होंने बताया, "मैंने श्री गांधी से कहा था कि चीन की नजर में भारत सोवियत संघ का पिट्ठू है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए चीन का यह भ्रम तोड़ना और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर आत्म निर्णय ले सकने का विश्वास दिलाना जरूरी है। चीन को हम अपना कोई भूभाग सौंप नहीं सकते, इसलिए चीन से अपनी विश्वसनीयता जमाने के लिए मैंने उन्हें समझाया कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हम तीन तरह से उसका सहयोग और बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एक, कंपूचिया से वियतनामी सैनिकों की वापसी की मांग। दूसरा, जेनेवा समझौते के तहत सोवियत संघ से यह मांग कि १५ फरवरी तक वह अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी करे। तीसरे, चीन को विश्वास दिलायें कि १९९१ में समाप्त होने वाली भारत-सोवियत सहयोग संधि का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। क्योंकि चीन का मानना है कि उक्त संधि उसके खिलाफ ही की गयी थी।"

स्वामी के अनुसार, "प्रधानमंत्री का दोटूक जवाब था कि दूसरे और तीसरे सुझावों को मानने का तो प्रश्न ही नहीं और पहले का सुझाव उनके सामने आज तक कभी प्रस्तुत नहीं हुआ। मैंने हंसकर उन्हें बताया, 'होता भी कैसे, जब आपको सुझाव देने वाले अरोड़ा और सेन जैसे सोवियतपरस्त सलाहकार हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपूचिया संबंधी सुझाव का वह परीक्षण करायेंगे। यात्रा के दो दिन पूर्व की हमारी दूसरी भेंट में प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि पहले सुझाव पर भी अमल नहीं हो सकता है। मैंने तत्काल उत्तर दिया, 'प्रधानमंत्रीजी आपके सलाहकारों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि चीन आपको बेनजीर भुट्टो अथवा अन्य अफ्रीकी नेताओं से अधिक इज्जत न बख्शे। आपको चीन में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।' मैंने उन्हें नेक सलाह दी थी। यात्रा का नतीजा मेरी समझ और सलाह की पुष्टि करता है।"

प्रतिकूल समय : यात्रा से निकले नतीजे से अधिक की अपेक्षा करना समुचित नहीं, ऐसा अधिकांश पर्यवेक्षक मानते हैं। उनके अनुसार यात्रा के लिए चुना गया समय ही भारत के लिए अधिक अनुकूल नहीं था। यद्यपि परस्पर संबंधों की शुरुआत १९७६ में वर्षों बाद राजदूतों की अदलाबदली से हुई थी। किंतु उस समय माओवाद के तहत सांस्कृतिक क्रांति में डूबे चीन में इससे अधिक की गुंजाइश नहीं थी। सही मायनों में चीन से संबंधों में सुधार का अवसर श्रीमती गांधी के समय में १९८३ में प्राप्त हुआ। पूर्व विदेश मंत्री व चीन में राजदूत रह चुके एपी वेंकटेश्वरन ने 'माया' को बताया, "उस समय भारत को स्पष्ट संकेत मिले कि चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ विचार करने और उत्तर पूर्व में मैकमोहन रेखा को मान्यता देने पर विचार करने को तैयार था। यह चाऊ-एन-लाई द्वारा १९५९ में प्रस्तावित एकमुश्त प्रस्ताव, जिसे देंग ने १९८२ में चीन की यात्रा पर गये एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सामने दोहराया था, से कहीं बेहतर था। श्रीमती गांधी ने इस पर विचार करते हुए यह फैसला लिया कि अगला वर्ष चुनाव होने के कारण समय उचित न था। चुनाव-पश्चात ही चीन की यात्रा पर जाने का फैसला किया। इसी बीच उनका निधन हो जाने से मामला अधर में रह गया। नतीजतन अवसर का लाभ नहीं उठाया जा सका।"

वेंकटेश्वरन के अनुसार १९८५ में उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चीन से पुनः बातचीत का दरवाजा खोलने की सलाह दी। इसके तहत यह भी सुझाव दिया गया कि पहले विदेश मंत्री को भेजकर स्थिति का आकलन कर लिया जाये। बाद में स्वयं प्रधानमंत्री चीन जायें। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के अन्य सलाहकारों की सलाह विदेश सचिव की सलाह के विपरीत रही। उन्होंने सुझाव दिया कि चीन की जगह अमरीका को प्राथमिकता देना अधिक हितकर होगा।

चीनी मामलों के विशेषज्ञ व दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो० मनोरंजन मोहंती का मानना है कि यदि प्रधानमंत्री १९८५-८६ में चीन गये होते, तो नतीजे कहीं बेहतर होते। कारण उस समय प्रचंड बहुमत, निर्विवाद व्यक्तित्व और पाक-साफ छवि वाले राजीव गांधी की स्थिति आज की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत होती और इससे चीन से मोलतोल की हैसियत भी बेहतर होती। किंतु अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री ने गलत राजनीतिक निर्णय लिया और अनुकूल मौके को हाथ से निकल जाने दिया।"

लेकिन प्रधानमंत्री को इस समय चीन नहीं जाना चाहिए था, ऐसा प्रो० मोहंती नहीं मानते। कोई भी आधुनिक दृष्टिकोण वाला प्रधानमंत्री वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इस यात्रा पर अवश्य जाता। इन्द्र कुमार गुजराल भी मौजूदा यात्रा के लिए चुने गये समय को गलत नहीं ठहराते। लेकिन उनके अनुसार प्रधानमंत्री ने एक चूक अवश्य की है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ विचार-विमर्श करके एक आम सहमति नहीं बनायी। यह बहुदलीय प्रणाली का एक आवश्यक अंग है। गुजराल का मानना है कि यदि गांधी ने आम सहमति बनायी होती, तो इस यात्रा से उनके हाथ कहीं अधिक मजबूत होते। उनके अनुसार भारतीय विदेश नीति की विशेषता निरंतरता और आम सहमति रही है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने आम सहमति को ही विदेश नीति का मूलाधार बनाया था। जहां तक निरंतरता का सवाल है, वह चाहे श्रीमती गांधी, लालबहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई की सरकार रही हो, न इसमें कोई बदलाव आया न आना चाहिए था। गुजराल ने 'माया' को बताया, "विदेश नीति अनिवार्यताओं पर आधारित होती है। उसे न तो भावनापरक बनाया जा सकता है और न व्यक्तिपरक।"

इस मापदंड पर राजीव गांधी की उपलब्धि खरी नहीं उतरती। चीन यात्रा के समापन पर जब उनसे उनकी उपलब्धि के बारे में प्रश्न किया गया, तो उनका दो टूक उत्तर था कि वे चीन के शीर्ष नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क बनाने में सफल रहे हैं।

बेजिंग (पीकिंग) में गांधी की शीर्ष नेताओं से हुई मुलाकातें महत्वपूर्ण रहीं। इनके द्वारा गत तीन दशकों से टूटे परस्पर सौहार्द और समझ का वातावरण कायम करने में सहायता मिली है, इस तथ्य को भी कोई नकारता नहीं। किंतु जिस प्रकार सरकारी मीडिया उसे एक नयी उपलब्धि बताकर ढिंढोरा पीट रहा है, वह भी सही नहीं है। क्योंकि चीन ने न तो ऐसा हर्षोल्लास प्रकट किया है, न ही ढिंढोरा पीटा। इसी कारण आम धारणा यह बनी है कि सीमा विवाद और अन्य द्विपक्षी मामलों को लेकर भारत के पल्ले कुछ भी नहीं आया है। इसी नाकामी पर परदा डालने के लिए देंग से मुलाकात और नयी उपलब्धि का लुभावना दृश्य पेश किया जा रहा है।

देंग की भेंट को चीनी सौहार्द-स्वीकृति का एक संकेत माना गया है और उसे जोरशोर से प्रचारित किया गया है। किंतु संकेतों में विश्वास रखने वाले चीन द्वारा भेजे अनेक संकेतों को या तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल समझने में असमर्थ रहा या जानबूझकर उसे अनदेखा करता रहा। चीन की रगरग से वाकिफ एक पर्यवेक्षक ने 'माया' को बताया कि इस यात्रा के ऐन पूर्व चीन ने अनेक ऐसी कार्रवाइयां कीं, जिनसे विश्व के सामने उसकी धाक जमे और किसी को जरा भी यह अहसास न हो कि वह भारत से सुलह-समझौते के लिए झुक रहा है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी

चीन सबसे पहले यह देखता है कि आप कितने पानी में हैं। उसी के अनुसार वह आपसे व्यवहार करता है और इज्जत देता है।

कदाचित इसीलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा के तीन दिन पूर्व उसने कराकोरम में सैन्य अभ्यास किये। यात्रा के दो दिन पूर्व उसने 'भारतीय विमान द्वारा सीमा का उल्लंघन करने' संबंधी विरोध पत्र देने में हिचकिचाहट नहीं दिखायी। जिस दिन राजीव गांधी चीन पहुंचे, उस दिन उसने सेटेलाइट मिसाइल छोड़ा और यात्रा के अंतिम दिन भी इसकी पुनरावृत्ति की। चीन के इरादे और संकेत स्पष्ट थे। वह भारत को उसकी औकात जताते हुए बता रहा था कि वह स्वयं कितनी बड़ी महाशक्ति है और इस रूप में वह भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को कितनी अहमियत देता है। रही-सही कसर तब पूरी हुई, जब चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग ने राजीव गांधी की अगुवाई के लिए हवाई अड्डे परं एक कनिष्ठ मंत्री को भेजा और स्वयं उनका सम्मान ग्रेट हाल के सेंट्रल हाल में किया। पर्यवेक्षक ने आगबबूला होकर कहा, "यह भारत को नीचा दिखाने की नीयत का परिचायक नहीं था तो और क्या था?"

समस्त संकेत प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने या उनकी यात्रा को प्रभावहीन बनाने के थे, ऐसा इन्द्र कुमार गुजराल नहीं मानते। इनका मूल उद्देश्य मात्र भारतीय अतिउत्साह को नियंत्रित करने का था। गुजराल ने 'माया' को बताया कि उन्हें अत्यंत विश्वसनीय चीनी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर चीन में भी उतनी ही उत्सुकता, संशय, चिंता व्याप्त थी, जितनी कि भारत में। चीन भारत को किसी प्रकार का गलत संकेत न दे दे, इसलिए जो निर्णय लिये गये, उन पर गंभीर और व्यापक विचार-विमर्श हुआ। एक समय यह लगभग तय हो गया कि प्रधानमंत्री ली पेंग स्वयं राजीव गांधी की अगुवाई के लिए हवाई अड्डे जायेंगे, किंतु अंतिम क्षणों में निर्णय बदल दिया। इसी प्रकार चेयरमैन देंग की भारतीय प्रधानमंत्री से किस दिन मुलाकात करायी जाये, इस पर भी घोर विचार-विमर्श चला। शुरू में पहले दिन ही मुलाकात का फैसला लेने के बाद फिर उसे तीसरे दिन कर दिया गया। किंतु भारत सरकार संकेतों को सही ढंग से समझ न पाने के कारण अपने अतिउत्साह पर काबू न पा सकी। गुजराल के अनुसार चीन ने अनेक सकारात्मक संकेत भी यात्रा के पूर्व और यात्रा के दौरान दिये हैं।

भारत चीन संबंधों का केन्द्र बिन्दु सीमा विवाद का मुद्दा है जो अपने आप में एक जटिल समस्या है। किंतु कोई भी वस्तुपरक विश्लेषण इस विवाद को निपटाने में हुई प्रगति का संकेत नहीं करता। वस्तुस्थिति यह है कि भारत की अब तक जो नीति रही है, उसको बदलने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। वेंकटेश्वरन के अनुसार अब तक भारतीय दृष्टिकोण यही था कि संबंधों में सुधार लाने से पूर्व सीमा को निपटाना आवश्यक होगा। इसके विपरीत चीनी दृष्टिकोण अन्य संबंधों में सुधार करने के बाद ही सीमा विवाद से निपटने का था। प्रधानमंत्री की यात्रा और उसके बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत को संबंध-संपर्क बढ़ाने के लिए मूलगामी परिवर्तन कर अपने इस रवैये में तब्दीली करनी पड़ी है। जाहिर है चीन इस मुद्दे पर अपनी मनमानी करवाने में सफल रहा।

सीमा विवाद के मसले पर संयुक्त कार्यदल के गठन के फैसले को बहुप्रचारित किया गया है। अधिकांश विपक्षी नेता इसे न तो कोई उपलब्धि मानते हैं, न पहले की आधिकारिक वार्ताओं से कुछ खास अलग। विशेषकर इसलिए कि इसका स्तर तक नहीं बढ़ाया गया। दोनों देशों के सचिव स्तर के अधिकारियों को ही यह कार्यभार सौंपा गया। भारत के मंत्री स्तर के सुझाव को चीन ने नामंजूर कर दिया। जब इसकी चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता से चली, तो उन्होंने कहा कि दोनों में साम्य कहां है? अंतर बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा संयुक्त कार्यदल एक टिकाऊ मशीनरी है। इसकी अपेक्षा पिछली बैठकें तदर्थवाद पर आधारित थीं। दूसरे पिछली बैठकों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत था। किंतु संयुक्त कार्यदल केवल सीमा विवाद पर विचार-विमर्श करेगा। साथ ही इसे सर्वेक्षण, महालेखा आदि की तकनीकी सहायता प्राप्त होगी जो सचिव स्तरीय पिछली आठ बैठकों को उपलब्ध नहीं थी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात से शीर्ष राजनीतिक समर्थन प्राप्त होगा। जवाबी सवाल भाजपा अध्यक्ष आडवाणी ने किया, "क्या अब तक की आठ बैठकें बिना किसी राजनीतिक समर्थन और दिशा-निर्देश के महज लीपापोती करने के लिए थीं?"

गुपचुप समझौता : संयुक्त कार्यदल को कैसा राजनीतिक दिशा-निर्देश मिलेगा, इसका कोई खुलासा संयुक्त विज्ञप्ति से नहीं होता है। अतः दो प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, खानापूरी के लिए इसका ऐलान कर दिया गया है और अभी तक दिशा-निर्देश के निर्णय नहीं लिये गये हैं। दूसरा, इस समस्या को सुलझाने के लिए जो मूलाधार बना है, उसका राजीव गांधी खुलासा

संबंध सुधारना क्यों बेहतर है ?

—मोहन गुरुस्वामी

यह उक्ति काफी प्रसिद्ध है कि किसी देश का न कोई स्थायी दोस्त है न स्थायी दुश्मन। सिर्फ उसके हित ही स्थायी होते हैं। हमारे स्थायी स्वार्थ हैं—हमारी समृद्धि, हमारी सुरक्षा और प्रभाव। इसलिए जो लोग भी पुराने विवादों को बनाये रखना चाहते हैं और बेकार का डर पाले बैठे हैं, वे सिर्फ आगे की चुनौतियों से ही मुंह नहीं फेर रहे हैं, बल्कि उनमें इतिहास की समझ नहीं है। ऐसा हमारे साथ एक बार पहले भी हुआ है और परिणामस्वरूप १९६२ में हम बुरी तरह पिट चुके हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इतिहास से सबक न लेने वाला आदमी इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त है।

पाकिस्तान से डर नहीं : हमारे लिए पाकिस्तान कोई बड़ा खतरा नही है। पाकिस्तान अगर भारत से लड़े, तो यह उसके लिए काफी घाटे का सौदा रहेगा। उसकी हालत १९७१ से भी बदतर होगी। इस बात का पता उन्हें भी है, हमें भी है और जिस किसी को भी इसमें दिलचस्पी है, उसे भी है। पाकिस्तान चाहे जो प्रचार कराये, सचाई यह है कि आज भी वह आर्थिक और सैनिक दृष्टि से भारत से बहुत पीछे है। उसकी सेना आकार में हमसे एक तिहाई है और प्रशिक्षण, उपकरण तथा कुशलता में उसका हमारी सेना से कोई मुकाबला नहीं है। उसका मुख्य टैंक है—एम-४८ जो हमारे टी-७२ के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। उसके मुख्य लड़ाकू विमान हैं चीनी ए-५ और फ्रांसीसी मिराज-५ जो हमारे जगुआर और मिराज-२७ की तुलना में बहुत घटिया विमान हैं। अगले दशक में मुख्य लड़ाकू विमान होंगे चीनी एफ-७ (फैंटम) जो हमारे मिग-२७ और एफएल विमानों से इक्कीस तो होंगे, लेकिन तब तक हमारे यहां मिग-२९ आ जायेंगे, जिन्हें अभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान माना जाता है। ये विमान फिलहाल हमारी वायुसेना की स्क्वाड्रन सेवा में मौजूद हैं। इसी प्रकार पाक नौसेना भी हमारे मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। वे सिर्फ क्रिकेट और हाकी की लड़ाई में हमारा मुकाबला कर सकते हैं।

लेकिन यह बात तभी तक हमारे हक में है जब हम एक मोर्चे पर लड़ रहे हों। पाकिस्तान और चीन से एक साथ लड़ने के लिए हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। आधुनिक युग में देशों के बीच लड़ाइयां एक दूसरे को पूरी तरह खतम करने वाली नहीं होतीं। हमारी कोशिश रहती है कि छोटी लड़ाइयां हों, उन पर देश-विदेश के मीडिया का ध्यान लगा रहता है। इसलिए ऐसी छोटी मुठभेड़ों में जीतने का बहुत महत्व होता है। ऐसी लड़ाइयों में कितने विमान गिराये गये और कितने टैंक ध्वस्त किये गये, यह अधिक महत्वपूर्ण होता है और इस बात की परवाह कम होती है कि लड़ाई से किन रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल किया जा सका। ऐसे में पाकिस्तान के ४० एफ-१६ विमानों के मुकाबले मिराज-२०००, या मिग-२९ तथा एम-१ टैंकों के मुकाबले हमारे अर्जुन टैंकों को खड़ा करना ही होगा। पाकिस्तानी शक्ति से मुकाबले के लिए यह बहुत जरूरी है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

> **हमें असली खतरा उत्तर में चीन से और हिंद महासागर में नवसाम्राज्यवादी ताकतों द्वारा एटमी हथियारों से लैस नौसैनिक बेड़े लाने से है। इनमें अमरीका और सोवियत संघ, दोनों ही शामिल हैं।**

असली खतरा : हमें असली खतरा उत्तर में चीन से और हिंद महासागर में नवसाम्राज्यवादी ताकतों द्वारा एटमी हथियारों से लैस नौसैनिक बेड़े लाने से है। इनमें अमरीका और सोवियत संघ, दोनों ही शामिल हैं। इनमें से किसी एक को कम खतरनाक मानना बेवकूफी है। ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत ले-देकर हमें चीन के साथ अपना सीमा विवाद सुलझा लेना चाहिए, ताकि विश्व राजनीति में अधिक प्रभाव जमाने की स्थिति बन जाये और चीन से हमें कोई खतरा न रह जाये। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थल सेना है और आगे भी रहेगी ही। जिन गैर-चीनी कम आबादी वाले इलाकों पर विवाद हैं, वे हमारी सीमा से जुड़े हुए हैं और उनके कारण हमें किसी वक्त भी लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि विवाद कायम रहने पर हमारा बहुत कुछ दांव पर लगा रहेगा और हर समय खतरा भी बना रहेगा। दूसरे शब्दों में यों कहा जाये कि अगर तिब्बत का कुछ हिस्सा टूटता भी है, तो इसका नुकसान चीन तो आसानी से बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि यह इलाका उसके लिए उतना मूल्यवान नहीं है। किंतु यदि हमें उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, जैसे बदरीनाथ का नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या हम सहन कर सकेंगे? क्या हम उन्हें (चीन) नेपाल या भूटान तक घुसने की इजाजत दे सकते हैं? जवाब होगा नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे पास उत्तरी सीमा पर फौज लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम थोड़ा भी सुस्त दिखे, तो इससे चीन को अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का मौका मिल जायेगा।

हिंद महासागर में बड़ी ताकतों की उपस्थिति से अलग तरह का खतरा पैदा हुआ है। अगर हम एटमी ताकत से लैस अपने से बड़ी इन शक्तियों के आगे झुक गये, तो एक तरह से हम फिर गुलाम हो जायेंगे और ऐसी स्थिति में भी कमजोर होने लगेंगे जब हमने अपनी ताकत इस क्षेत्र में दिखानी शुरू की है। १९७१ में जब हमारी सेना ढाका में घुसने की तैयारी कर रही थी, तो निक्सन ने एटमी मिसाइल युक्त सातवां बेड़ा 'इंटरप्राइज' भेजा था। अगर ऐसा ही कोई बेड़ा हमें उत्तरी श्रीलंका से निकलने का आदेश दे, तो क्या होगा? क्या सिर्फ राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद ही हमारा रखवाला रहेगा? जो देश एटमी हथियार न बनाने की एकतरफा घोषणा की वकालत करते हैं, उन्हें इन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग पाकिस्तान के साथ 'आपसी एटमी अप्रसार संधि' कराना चाहते हैं, जैसा कि बेनजीर भी चाहती हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करके हम अपने देश को एटमी ब्लैकमेल की स्थिति में नहीं पहुंचा देंगे? पाकिस्तान न तो एक क्षेत्रीय ताकत है और न ही उसके सामने भारत जैसे खतरे हैं। पश्चिमी देश, खासकर अमरीका, बेनजीर का इस्तेमाल करके एटमी अप्रसार संधि और हथियार घटाने की बात करके हमें पाकिस्तान की बराबरी पर ला देना चाहते हैं। पाकिस्तान को किसी चीनी खतरे का सामना नहीं करना है, इसलिए अगर वह भारत से खतरा न महसूस करे, तो आसानी से अपने हथियारों की कटौती कर सकता है। किंतु हमारा एटमी अप्रसार संधि के लिए तैयार हो जाना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्थिति में और पाकिस्तान की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। ■

इंद्रजीत गुप्त

यात्रा से रातोरात परिवर्तन या किसी विशेष उपलब्धि की आशा प्रधानमंत्री को नहीं थी, ऐसा भाकपा नेता इंद्रजीत गुप्त का दावा है।

करने को तैयार नहीं, क्योंकि यह चुनाव वर्ष है और विपरीत प्रतिक्रिया का जोखिम वह उठा नहीं सकते। यद्यपि लंदन से प्रकाशित 'द इकानामिस्ट' पत्रिका के इस समाचार का खंडन किया गया है कि राजीव गांधी ने यात्रा के पहले दिन ही चीन द्वारा मैकमोहन रेखा की स्वीकृति के बदले अक्साई चिन देने का आश्वासन दे दिया है। किंतु जानकार सूत्रों का मानना है कि ऐसा होना असंभव नहीं।

ज्ञात रहे कि अक्साई चिन सामरिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्व का स्थान नहीं है। वह एक प्रतिष्ठा का मुद्दा अधिक है। उल्लेखनीय है कि चीनी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जब संसद में पक्ष-विपक्ष के तीखे प्रश्नों का सामना करना पड़ा, तो उनका जवाब था कि उक्त क्षेत्र का कोई विशेष महत्व नहीं, क्योंकि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इस पर कांग्रेस के ही महावीर अधिकारी ने पलटकर जवाब दिया था, "पंडितजी, मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं, किंतु मैं इसे गंवाना नहीं चाहता।" तब से अब तक अक्साई चिन तो प्रतिष्ठा और विवाद का मुद्दा बना ही रहा है, साथ ही नेफा क्षेत्र भी इससे जुड़ गया है।

मूल प्रश्न यह है कि सीमा विवाद का हल कैसे होगा? प्रख्यात राजनीतिक पर्यवेक्षक निखिल चक्रवर्ती के अनुसार या तो भौगोलिक स्थल को आधार बनाकर या ऐतिहासिक दावों और उनके विपरीत किये गये अन्य दावों के आधार पर अथवा मौजूदा यथार्थ को मोटे तौर पर स्वीकार करके उसमें छोटे-मोटे परिवर्तनों के सुझाव देने के आधार पर इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। किंतु इनमें से कोई भी समस्या रहित साबित नहीं होगा। अगर जलसम्भर के सिद्धांत को पूर्वी क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्र के उन कराकोरम पहाड़ियों में समस्या के हल को कैसे ढूंढ़ा जा सकता है, जहां एक से अधिक जलसम्भर हो सकते हैं? विशेषकर तब जब हम कोयनलुन पहाड़ियों को सीमा मानने के अपने फैसले पर डटे रहे हैं और चीन को यह कतई मंजूर नहीं।

इसी प्रकार यदि हम ऐतिहासिक दावों को दिशानिर्देश बनायेंगे, तो चीनी अरुणाचल प्रदेश के बड़े भाग पर यह कहकर दावा कर रहे हैं कि मैकमोहन रेखा खींचने के पहले यह हिस्सा ल्हासा के अधीन था। अगर हम मौजूदा यथार्थ के सिद्धांत को मानते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के बड़े भूभाग पर चीन के दावों के परित्याग के बदले में भारत को पश्चिमी क्षेत्र में अपने दावों को त्यागना पड़ेगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसे भारत ने १९६० में चाउ-एन-लाई की दिल्ली यात्रा के दौरान ठुकरा दिया था और १९८२ में श्रीमती गांधी ने अस्वीकारा था।

इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पुराने एकमुश्त प्रस्तावों के अलावा चीन उत्तर-पूर्व में त्वांग क्षेत्र पर भी अपना दावा जता रहा है, जिसे भारत कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कारण, सामरिक दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्र है। इसे दे देने से समूचा गंगाघाटी का क्षेत्र असुरक्षित हो जायेगा। इसके अलावा इसके विकास में हमारी सेनाओं ने अपनी जी-जान लगा दी है। अतः प्रबल सैन्य विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

चीन ने भारत की इस कमजोरी और दुविधा का भरपूर लाभ उठाते हुए तिब्बत के मामले में भारत को सांसत में डाल दिया है। इस बारे में प्रधानमंत्री की स्थिति कितनी विषम और विचित्र रही, यह इससे स्पष्ट हुई कि उन्होंने स्वयं तो यह ऐलान किया कि तिब्बत की चर्चा करने का उन्हें वक्त नहीं मिला, किंतु उनकी यात्रा के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति और अधीकृत चीनी संचार माध्यमों ने यह बताकर कि चीनी प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने राजीव गांधी से तिब्बत पर विस्तृत बातचीत की, उन्हें झूठा साबित कर दिया।

प्रश्न यह उठता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या उनको कमजोर पाकर चीन ने तिब्बत के संबंध में उनसे कोई ऐसा आश्वासन ले लिया है जिसे वे ऐलानिया जाहिर करने में भयभीत हैं? चीन को नजदीक से जानने वालों का विचार है कि चीन भारत में असंतुष्ट चीनियों को दबाने के लिए राजीव गांधी से तो अपेक्षा रखता ही है, साथ ही राजीव गांधी के माध्यम से दलाई लामा पर यह दबाव डालना चाहता है कि वे (दलाई लामा) चीन की शर्तों पर सुलह के लिए तैयार हो जायें।

प्रो० मोहंती तिब्बत के मामले को विशेष तूल नहीं देते। उनका मानना है कि इस समय जो किया-क़हा गया, वह १९५४ से चला आ रहा है। चीनी इस बारे में कम-से-कम हमारी सहमति की पुनः पुष्टि चाहते थे। यदि सवाल कम-से-कम का था, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का अंग मानने के लिए चीन से ऐसा ही कोई वक्तव्य क्यों नहीं जारी कराया जा सका? इसी प्रकार यदि वे तिब्बतियों से चीन विरोधी गतिविधियों के प्रति आशंका, चिंता व्यक्त कर सकते थे, तो हमने कम-से-कम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को हथियार देने के प्रति अपनी चिंता और आशंका क्यों नहीं व्यक्त की? इस पर टिप्पणी की सुब्रह्मण्यम स्वामी ने, "जाहिर है, चीन के आगे राजीव गांधी कुछ भी कहने-करने और खाली हाथ वापस आने को विवश थे।"

प्रश्न उठता है कि राजीव गांधी सीमा-विवाद के हल के लिए संयुक्त कार्यदल के गठन, सीमा क्षेत्र पर शांति व्यवस्था करार के अलावा तीन मामूली समझौते—परस्पर विमान सेवा, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग तथा परस्पर व्यापार समझौते की जो उपलब्धि लेकर वापस आये हैं, क्या वह उससे कुछ अधिक हासिल कर सकते थे? जहां तक संयुक्त कार्य दल के गठन और इसकी भावी सफलता का सवाल है, इसकी विस्तृत चर्चा पहले ही की जा चुकी है। रही सीमा क्षेत्र पर शांति व्यवस्था की बात, तो वेंकटेश्वरन के अनुसार इस मुद्दे पर निर्णय १९८१ में सचिव स्तर की पहली बैठक में ही लिया जा चुका था। अतः यह कोई नयी बात नहीं है। १९८६ में उत्तर पूर्व क्षेत्र में हुए तनाव के अतिरिक्त इस पूरे दौर में कोई विशेष तनाव नहीं रहा। इसी प्रकार जो तीन अन्य समझौते हुए हैं, सामान्य हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में ये क्या सुधार लायेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। किंतु दशकों बाद टूटे धागों को जोड़ने की जहां तक बात है, उसमें रातोरात कामयाबी हासिल हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विशेषकर तब जब दूसरी ओर चीन जैसा देश हो जो न कोई मामला जल्दी उठाता है और न ही जल्दी हल करता है। ज्ञात रहे कि मैकमोहन रेखा की बात १९१७ में चली और चीनी प्रतिक्रिया उस पर १९६०-६२ में हुई। कदाचित इसीलिए राजीव गांधी ने जहां समयबद्ध तरीके से सीमा विवाद सुलझाने की बात कही, वहीं चीन ने बिलकुल चुप्पी साध ली। नतीजतन राजीव गांधी भी अब इस बात को दोहरा नहीं रहे हैं।

ऐसी स्थिति में अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षक सवाल करते हैं कि चीन के बारे में सब कुछ जानने-समझने के बाद भी राजीव गांधी आखिर वहां किस उम्मीद पर गये थे? यात्रा से रातोरात परिवर्तन या किसी विशेष उपलब्धि की आशा प्रधानमंत्री को नहीं थी, ऐसा भाकपा नेता इंद्रजीत गुप्त का दावा है। 'माया' को उन्होंने बताया कि यात्रा से पूर्व राजीव गांधी की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से और उनसे (इंद्रजीत गुप्त से) हुई बातचीत में उन्होंने (राजीव गांधी ने) स्पष्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं है। मूल उद्देश्य बंद दरवाजे खोलना और टूटे संबंधों को जोड़ने का था। प्रधानमंत्री ने यह भी जाहिर किया था कि यदि वे दोनों पक्षों की सीमा पर तैनात सैनिकों के परस्पर तनाव व मुठभेड़ों की संभावनाओं को कम करने के लिए थोड़ा भी पीछे हटा सके, तो भी वे संतुष्ट रहेंगे। यह दूसरी बात है कि राजीव

गांधी इसमें भी फिलहाल कामयाब नहीं हुए हैं।

"कामयाब होते भी कैसे जबकि उनका मूल: उद्देश्य कुछ और था?" जनता दल महासचिव अजीत सिंह ने 'माया' से यह टिप्पणी करते हुए कहा, "राजीव गांधी अपनी व्यक्तिगत छवि को मांजने-चमकाने के लिए ही चीन गये थे। राष्ट्रीय हित और लाभ के लिए नहीं। दरअसल भावी चुनावों को मद्देनजर रख अपनी गद्दी बचाने में उनकी अधिक दिलचस्पी थी।" अजीत सिंह ही नहीं, अन्य विपक्षी नेता और अधिकांश पर्यवेक्षक भी मानते हैं कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय दबावों की अपेक्षा मूलतः अपनी राष्ट्रीय विवशताओं के कारण वहां गये थे। चुनाव वर्ष में कोई भी दूसरा देश बड़ी संधि करने को तैयार नहीं रहता, क्योंकि इस बात का भरोसा नहीं रहता कि जो हस्ती आ रही है वह गद्दीनशीं रहेगी भी या नहीं। राजीव गांधी इस तथ्य से निश्चित ही अनभिज्ञ न रहे होंगे। विशेषकर इसलिए कि इसके पूर्व श्रीमती गांधी स्वयं चुनाव के बाद चीन जाना चाहती थीं, पहले नहीं। किंतु वे इस तथ्य को भी भलीभांति जानते हैं कि रिचर्ड निक्सन १९७२ के चुनाव वर्ष में अपनी चीन यात्रा को भुनाने में सफल हुए थे। इस समय चीन जाने के पूर्व राजीव गांधी के सम्मुख अपनी मां श्रीमती गांधी का वह उदाहरण भी था, जब वामपंथियों का समर्थन प्राप्त कर वह गद्दीनशीं हो गयी थीं। इस मापदंड पर उनकी यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण और सफल रही है।

इस विषय में 'माया' की जब एक विपक्षी नेता से बातचीत चली, तो उनका उत्तर था, "राजीव गांधी की चीन यात्रा का मुख्य लक्ष्य अवश्य ही वामपंथियों का समर्थन हासिल करके विपक्ष को विभाजित करना था।" राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए ऐसी अनुकूल स्थिति बनाने में राजीव गांधी सोवियत संघ और चीन दोनों का सहयोग हासिल करने में सफल रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों ने 'माया' को बताया कि माकपा की हाल की तिरुअनंतपुरम की कांग्रेस में भारत के संबंध में न केवल सोवियत संघ व चीन के प्रतिनिधियों के स्वर लगभग एक से थे, बल्कि दोनों ने ही इस महत्वपूर्ण बात की घोषणा की कि "उनका देश और पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों और कांग्रेस-इ से संबंध बनाने-बढ़ाने की आकांक्षी हैं"। संकेत भारतीय कम्युनिस्टों के गले उतर गया है, यह राजीव गांधी की चीन से वापसी के तुरंत बाद वामपंथी पार्टियों और बहुगुणा तथा उन्नीकृष्णन जैसे वामपंथी झुकाव वाले नेताओं के एक मंच पर आने और राष्ट्रीय मुहिम चलाने की घोषणा से उजागर है। अगले चुनावों में कम्युनिस्टों को यदि उन्हें 'स्वाभाविक सहयोगी' करार देने वाले वीपी सिंह कम जचें और राजीव गांधी अधिक प्रगतिशील लगें, तो आश्चर्य नहीं।

चीन-पाक यात्राओं से छवि में जो सुधार हुआ है, उसका राजीव गांधी को दोहरा राजनीतिक लाभ मिलेगा, ऐसा भवानी सेन गुप्त मानते हैं। एक ओर इसके चलते जहां व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ है, वहीं दूसरी ओर उनका बढ़ा कद अपनी पार्टी पर गिरफ्त और मजबूत करने में सहायक हुआ है। यही नहीं, इस यात्रा द्वारा राजीव अपने ऊपर लगी निष्क्रियता, नीति और दिशाहीनता की कालिमा को कुछ हद तक धो सकने में सफल हुए हैं।

प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के तुरंत बाद की गयी पाकिस्तान यात्रा भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह राजकीय यात्रा न होकर दक्षेस शिखर सम्मेलन के तहत की गयी थी। किंतु उस मौके पर भारत-पाकिस्तान के बीच जो संक्षिप्त द्विपक्षी वार्ताएं हुईं, उन्होंने दक्षेस सम्मेलन को ही पृष्ठभूमि में डाल दिया। यहां तक कहा जाता है कि इससे अनेक दक्षेस नेता मन-ही-मन कुड़मुड़ाये भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव गांधी को पाकिस्तान से जो 'एलर्जी' थी, उसका यात्रा से निदान हुआ। उल्लेखनीय है कि जनरल जिया के अनेक बार यहां आने और पाकिस्तान यात्रा का दावतनामा देने के बाद भी राजीव गांधी कभी उन्मुख न हुए। यहां तक कि दक्षेस के अध्यक्ष के

हरकिशन सिंह सुरजीत

सुरजीत ने इस संबंध में 'माया' का ध्यान देंग के उस वक्तव्य की ओर दिलाया, जिसमें उन्होंने अतीत को भुलाने का सुझाव दिया।

आर्थिक संबंधों में सुधार जरूरी

प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के संभावित नतीजों के बारे में राजनीतिकों और राजनीतिक पार्टियों के परस्पर विरोधी विचार हैं। पत्र-पत्रिकाओं का स्वर भी निंदा-स्तुति मिश्रित था। किंतु व्यवसायियों और उनके संगठनों ने चुप्पी साधी है। उन्होंने न तो संयुक्त विज्ञप्ति की सराहना की है और न आलोचना-निंदा का एक शब्द कहा है।

क्या इसका मतलब है कि भारत के विशाल व्यावसायिक समूहों ने समाजवादी गुट के दूसरे सबसे बड़े देश (सबसे बड़ा सोवियत संघ) के मैत्रीपूर्ण संबंधों का यकायक स्वागत करने की ठानी है? अथवा क्या उनकी चुप्पी का अर्थ है कि वे अपने विचारों को प्रकट करना नहीं चाहते, गोकि वे अंदर से नाखुश हैं?

इनमें पहली बात सच लगती है, दूसरी नहीं। कदाचित उनका तिब्बत व अक्साई चिन के मुद्दों पर वही नजरिया है, जो राजीव गांधी के आलोचकों का है, किंतु आर्थिक क्षेत्र अलग मुद्दा है। व्यवसायियों के लिए आर्थिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे ही व्यवसाय फलता-फूलता है।

संभावनाओं की गणना दो प्रकार से की गयी है। एक, पड़ोसी देश से मैत्रीपूर्ण संबंध का देश के अर्थतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा देश व उसके व्यवसायियों को विभिन्न प्रकार की क्या आर्थिक उपलब्धियां होंगी?

आर्थिक संबंधों को पहले लें। ऐसे अनेक तरीके हैं, जिससे दोनों देश लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे आसान और उजागर तरीका व्यापार है। हरेक देश खरीदता भी है और बेचता भी है। यह तब आसान होता है, जब एक पक्ष के पास दूसरे देश को बेचने के लिए वह जिंस हो जिसका उत्पादन दूसरा देश नहीं करता या भरपूर उत्पादन नहीं करता।

मौजूदा समय में भारत-चीन के बीच व्यापार साधारण है। दोनों देशों की कुल बिक्री (अर्थात कुल आयात-निर्यात) मात्र लगभग १९३ करोड़ रुपए थी। भारत के नजरिए से यह उसके कुल आयात-निर्यात का मात्र आधा प्रतिशत है। चीनी नजरिए से यह और भी नगण्य था। भारत से उसके कुल व्यापार का भाग पूरी दुनिया से उसके १९८८ में होने वाले व्यापार के एक दिन के बराबर है। भारत के अन्य देशों से व्यापार की तुलना में यह इतना बुरा भी नहीं है। मसलन जर्मन जनवादी गणराज्य से हमारा व्यापार १७५ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। रूमानिया से २५० करोड़ रुपए के लगभग है। जबकि भारत इन देशों से २० वर्ष से ज्यादा समय से व्यापार कर रहा है।

अधिक अहम सवाल यह है कि व्यापार कैसे बेहतर बन सकता है? अभी भारत चीन से कृषि उत्पाद मसलन दालें, तिलहन आदि खरीदता है। इसके अलावा अधिकांश निर्मित सामान, जिसकी दोनों देशों को जरूरत होती है, देश में ही बनते हैं। इस तर्क से व्यापार के अधिक विस्तार की संभावना नहीं लगती।

इंद्र कुमार गुजराल

गुजराल बोले, "भारतीय भावनाओं की कद्र करते हुए यदि चीन शीघ्र ही कोई महत्वपूर्ण ऐलान करे, तो आश्चर्य न होगा।"

रूप में जब उन पर (राजीव गांधी पर) सदस्य देशों की यात्रा की जिम्मेदारी थी, तब भी उन्होंने न केवल पाकिस्तान न जाने का फैसला लिया, बल्कि वहां जाने के बारे में पूछे गये एक सवाल पर तत्कालीन विदेश सचिव एपी वेंकटेश्वरन की अति नाटकीय ढंग से उसी समय छुट्टी भी कर दी।

पाकिस्तान के प्रति प्रधानमंत्री के बदले रुख का प्रमुख कारण वर्षों बाद हुई वहां लोकतंत्र की बहाली और निर्वाचित प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का सत्तासीन होना है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत सदैव पाकिस्तान से मैत्री और सहयोग का पक्षधर रहा है। किंतु पिछले अनेक वर्षों की राष्ट्रपति जिया की फौजी तानाशाही और उसकी पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी तथा तोड़फोड़ करने वाली शक्तियों को सहायता-समर्थन दे कर भारत को सांसत में डालने की गतिविधियां, परस्पर सामान्य संबंध बनाने में बाधक रहीं। आज संबंध सुधारने का अवसर आते ही हम उसे दोनों हाथों से बटोरने को उत्सुक हैं।

स्मरणीय है कि दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री स्वातंत्र्योत्तर भारत की नयी पीढ़ी के प्रतिनिधि, आधुनिक शिक्षा-दीक्षा से लैस और रौशनख्याल हैं। इसके तहत पुराने जख्मों को भुलाकर परस्पर संबंध बनाने की दिशा में दोनों ही का उन्मुख होना आश्चर्यजनक नहीं है।

तीन समझौते : इस सौहार्दपूर्ण यात्रा के बाद किये गये तीन समझौते संबंधों के सुधार की दिशा में अवश्य एक अगला कदम हैं। वैसे एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का समझौता कोई नया नहीं है। राष्ट्रपति जिया व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की १७ दिसंबर, १९८५ की मुलाकात में इस पर मौखिक सहमति हो चुकी थी। परस्पर तनाव की वजह से इसको कभी औपचारिकता प्रदान नहीं की गयी। किंतु यही समझौता आज भारत में दोहरे विरोध का मुद्दा बना है। एक तो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान भी विदेश मंत्रालय को अलग-थलग रखा, उससे इस समझौते का पूरा श्रेय पाकिस्तान ने हथिया लिया। दूसरे मोहन गुरुस्वामी जैसे सैन्य विशेषज्ञ इसमें अमरीका का सीधा हाथ देखते हैं। ज्ञात रहे कि अमरीका भारत पर परमाणु परिसीमन संधि (नान प्रालिफरेशन ट्रीटी-एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालता रहा है। भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है। इस संबंध में पाकिस्तान से किया गया समझौता कुछ और नहीं, मात्र द्विपक्षी एनपीटी है। गुरुस्वामी ने 'माया' से कहा कि इस समय मुख्य सवाल एक दूसरे के ठिकानों पर हमला करने न करने का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करना था कि वह इस कार्यक्रम का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए नहीं, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा। गुरुस्वामी की इस आशंका की पुष्टि पाकिस्तान द्वारा हाल में किये गये इस ऐलान से हो जाती है कि वह शीघ्र ही अपना परमाणु परीक्षण चीन के किसी भूभाग में करेगा। इससे ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दोनों देशों की यात्रा के प्रभावों का संदर्भ बदल जाता है।

गंभीर मतभेद, परस्पर संदेह और टकराते हितों के मौजूदा माहौल में पाकिस्तान से इससे कुछ अधिक पाया जा सकता था, ऐसा प्रसिद्ध राजनीतिक पर्यवेक्षक निहाल सिंह नहीं मानते। उनके अनुसार लगभग तीन दशक बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गयी पाक यात्रा से अधिक विवेकपूर्ण, तार्किक बातचीत और संबंधों में सुधार की आधारशिला मात्र ही डाली जा सकती थी और यह राजीव की पाक यात्रा से बखूबी हुआ है।

भारत-पाकिस्तान के संबंधों के सुधार में राजीव गांधी की अपेक्षा बेनजीर भुट्टो के हाथ कहीं अधिक बंधे हुए हैं। भावी संबंध कितने सुधरेंगे, यह इस पर निर्भर करेगा कि विषम परिस्थितियों से जूझती बेनजीर भुट्टो कब तक अपना अस्तित्व बचा पाती हैं और अपनी स्थिति कितनी सुदृढ़ कर सकेंगी। कारण, सबसे बड़ा खतरा उनके अमरीका अथवा पाक सेना की कठपुतली बन जाने का है। एक

किंतु भविष्य को देखने का एक और तरीका है। चीनी अर्थतंत्र जिस तरीके से विकसित हो रहा है, उस पर एक नजर डालें। चीन में व्यापक पैमाने पर नये उत्पाद लोकप्रिय हो रहे हैं। इससे अनेक भारतीय व्यवसायियों को चीन का विकसित बाजार प्राप्त हो सकता है। इस बाजार की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि चीन में लगभग २० करोड़ परिवार हैं। २० करोड़ में ४० प्रतिशत यानी ८ करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनकी उपभोक्ता जिस खरीदने की सामर्थ्य है।

इसी प्रकार चीन में भारतीय पूंजी निवेश की भी बेहतर संभावना है। चीन ने विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया है। भारतीय व्यवसायियों को अमरीकी-यूरोपीय कंपनियों से नयी तकनीक हासिल करने की स्थिति में चीन में नये उद्योग लगाने में सहूलियत होगी। भारत-चीन दोनों ही विदेशी तकनीक प्राप्त करने को उत्सुक हैं।

अमरीकी यह भलीभांति समझते हैं कि उनका चीन से संबंध अच्छा होना चाहिए। अमरीका-चीन संपर्क संबंधी अमरीकी राष्ट्रीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन अगली शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। यह पहले से ही एक आर्थिक शक्ति बन चुका है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। चीन का कुल विदेश व्यापार जो १९७७ में २२५०० करोड़ रुपए था, वह १९८८ में बढ़कर १५०,००० करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

चीन की भी भारत से व्यापार संबंध बढ़ाने में समान रुचि है। चाइना कोल इंफार्मेशन सेंटर (चीन कोयला सूचना केंद्र) भारत के लिए एक व्यावसायिक डाइरेक्ट्री प्रकाशित करने जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के व्यवसायियों और फर्मों के बारे में तमाम तथ्य एकत्र करना है, जिसके तहत खरीद-फरोख्त की जमीन तैयार की जा सके।

इसके अलावा चीन ने दोनों देशों के बीच ऐसी समुद्री जहाज सेवा का प्रस्ताव किया है, जिससे एक देश का जहाज दूसरे देश एक महीने में कम से कम दो बार पहुंच सके। इसमें भारतीय व्यवसायियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय व्यवसायियों ने गत चार-पांच वर्षों में चीन की अनेक बार यात्राएं की हैं। यही कारण है कि भारतीय व्यवसायियों ने राजीव गांधी की चीन यात्रा पर नाराजगी जाहिर नहीं की है।

देश के लिए एक बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी देश से मैत्रीपूर्ण संपर्क-सहयोग से निश्चित रूप से लाभ हासिल किया जा सकता है। खासकर जबकि पड़ोसी देश सीमा से लगा हो तथा मात्र कुछ हजार किलोमीटर दूर बसा हो। ऐसे पड़ोसी के कारण ही हमें अपनी कुल सेना के एक-तिहाई भाग से अधिक को उस क्षेत्र में तैनात करना पड़ता है और सुरक्षा व्यय बढ़ता है, जिसे पूरा करने के लिए आम आदमी से कर के रूप में रुपए उगाहे जाते हैं।

यदि पड़ोसी से संबंध मधुर हो जायें, तो सुरक्षा व्यय में कमी आयेगी और जनता पर करों का बोझ कम होगा। सुरक्षा व्यय में वृद्धि की रफ्तार कम हो जाने से सरकारी खर्च भी कम हो जायेगा।

राजीव गांधी को राजनीतिक स्तर पर चीन से चाहे जो भी उपलब्धि हुई हो, यदि आर्थिक संबंधों में सुधार होता है, तो उनकी यात्रा भारत और चीन दोनों के लिए फलप्रद होगी।

—कुमारेश चक्रवर्ती

ओर भारत को यह आश्वासन देना कि वे पंजाब और जम्मू-कश्मीर में हर प्रकार की उत्तेजनापूर्ण कार्रवाइयां बंद करेंगी और दूसरी ओर हज पर जाते हुए जेद्दा में यह ऐलान करना कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अपना हक बरकरार रखेगा, उनकी दुविधाजनक और विषम स्थिति का द्योतक है अथवा उनकी दोहरी चाल का, कहना कठिन है। कारण, भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों के हुक्मरानों की, गद्दीनशीं रहने के लिए भारत विरोधी विष वमन करना एक आवश्यक रणनीति रही है।

बेनजीर के संबंध में दुविधाजनक स्थिति भारत की भी है। जाहिर है कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बेनजीर को हर प्रकार के संबंध व सहयोग की दरकार है। इसमें यदि भारत का अतिउत्साहित हो, आवश्यकता से अधिक सहायता उनकी (बेनजीर की) कुरसी बचाने की जगह हिला सकती है। इसके ठीक विपरीत हिचकिचाहट और मद्धिम चाल से मौका हाथ से फिसल जाने का भी खतरा है।

निःसंदेह राजीव गांधी की चीन-पाक यात्राएं अनेक मायनों में एक अच्छी पहलकदमी रही हैं। आज के युग में पड़ोसी देशों से अलग-थलग रहकर या दुश्मनी मोल लेकर कोई भी देश शांति-व्यवस्था और विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अमन-चैन आम भारतीय की चाह है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। इसे स्थापित करने के लिए यदि कोई लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़े, तो उसे भी आलोचना का मुद्दा बनाना उचित नहीं, क्योंकि हठवादिता एक ऐसी विलासिता है, जिसे वर्तमान युग में कोई भी देश अपना नहीं सकता—बशर्ते अपनी नीति बदलने में न कोई राष्ट्रीय अहित हो न आत्मसमर्पण।

कोई चारा नहीं था : प्रश्न यह उठता है कि यात्राएं इस मापदंड पर कैसी उतरती हैं? राजीव गांधी ने नीति परिवर्तन की ओर कदम अवश्य बढ़ाया है किंतु कुछ ठोस समर्पण किया है, ऐसा माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं मानते। उनके अनुसार चीन के बारे में राजीव गांधी के विकल्प अत्यंत सीमित थे और तीन-सूत्री थे। एक, यथास्थिति बरकरार रखें। दूसरे, चीन अधिकृत भूमि को बाहुबल से हासिल करने की कोशिश करें। तीसरे, वार्ता द्वारा सीमा विवाद हल करें। पहले दो मुद्दों पर अमल करना भारत के हित में कतई नहीं है। अतः उनके पास सुलह-सफाई के अलावा कोई चारा नहीं था। भारत के लिए चीन की ठकुरसुहाती करना अनपेक्षित है, तो चीन से भी यह उम्मीद रखना कि वह फर्माबरदार बन जाये, गलत है। दोनों के लिए लेन-देन का रवैया अपनाना आवश्यक है। सुरजीत ने इस संबंध में 'माया' का ध्यान देंग के उस वक्तव्य की ओर दिलाया, जिसमें उन्होंने अतीत को भुलाने का सुझाव दिया। समस्त दोष मात्र भारत के मत्थे न मढ़ने का इससे अच्छा संकेत और कोई नहीं है, सुरजीत ने कहा। गुजराल बोले, "भारतीय भावनाओं की कद्र करते हुए यदि चीन शीघ्र ही कोई महत्वपूर्ण ऐलान करे, तो आश्चर्य न होगा।" इंद्रजीत गुप्त ने जोड़ा, "यहां तक कि कुछ समय बाद वह प्रत्यक्ष रूप से १९६२ की घटना को भूल मान खेद भी प्रकट कर सकते हैं।"

भारत-चीन संबंधों में सुधार का प्रभाव बहुत व्यापक होगा, ऐसा लगभग सभी लोग मानते हैं। दुनिया की एक-तिहाई आबादी वाले इन दो सबसे बड़े देशों के संबंधों में सुधार से जहां परस्पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना की नयी जमीन तैयार होगी, वहीं उनके विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभरने की संभावना भी तीव्र हो जाती है। भारत-चीन संबंधों व चीन-सोवियत संबंधों में सुधार एशिया में स्थिरता पैदा कर अमरीकी दखलंदाजी पर लगाम लगाने में भी सफल हो सकता है। अनेक पर्यवेक्षक सोवियत संघ द्वारा भारत-चीन संबंधों में सुधार के प्रोत्साहन पीछे यही रणनीति देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वें चीन को भारत के खिलाफ तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल न कर सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत की स्थिति बेहतर रहेगी।

बेहतर सुरक्षा वातावरण के चलते सैन्य कटौती की जाये या नहीं, दोनों ही विवाद के मुद्दे हैं। वरिष्ठ जनता सांसद जयपाल रेड्डी ने 'माया' से कहा, "संबंधों में थोड़े सुधार के चलते हम अपने सुरक्षा व्यय में कटौती नहीं कर सकते। सुरक्षा दायित्व और नीति का संबंध बदलते राजनयिक समीकरणों से नहीं होता है, बल्कि शक्ति-संतुलन के अधिक टिकाऊ व भरोसेमंद तत्व पर आधारित होता है।"

मौजूदा राजनीतिक व विशेषकर सैन्य परिदृश्य में जहां एक ओर अमरीकी अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैस पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तैयारी में हो तथा चीन ११ आईसीबीएम, (इंटर कांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल), सैकड़ों आईआरबीएम (इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल) तथा अनेक परमाणु बमों से युक्त हो और हिंद तथा प्रशांत महासागरों पर रूस और अमरीका की गिद्ध-दृष्टि हो, भारत के लिए सैन्य खर्चों में कटौती करना तो दूर, तैयारी में ढिलाई बरतना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। एक सैन्य विशेषज्ञ ने 'माया' से कहा, "किसी देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हमारी तैयारी पूरी हो। पड़ोसी देशों से सीमा विवाद का हल होना इतना आसान काम नहीं और हो भी जाये, तो इस बात की गारंटी नहीं कि कल किसी बात को लेकर हमारे बीच कोई विवाद उभरेगा ही नहीं।"

नेहरू और माओ

जवाहरलाल नेहरू को जब संसद में पक्ष-विपक्ष के तीखे प्रश्नों का सामना करना पड़ा, तो उनका जवाब था कि उक्त क्षेत्र का कोई विशेष महत्व नहीं।

राजीव गांधी की चीन-पाक यात्राओं से देश को अंततः कितना लाभ होगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा। राजीव गांधी को राजनीतिक लाभ पहुंचा है, चाहे वह वामपंथियों के समर्थन का हो अथवा मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का, यह भी कोई विशेष आलोचना या चिंता का मुद्दा नहीं। विश्व के सभी नेता चाहे वे अमरीका के रिचर्ड निक्सन हों, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर हों या भारत की इंदिरा गांधी-प्रत्येक ने समय-समय पर अपनी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहलकदमियों द्वारा लाभ उठाने का सदैव प्रयास किया है। फर्क इतना है कि राजीव गांधी को हाल में राष्ट्रीय क्षेत्र की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। जाहिर है कि इसका लाभ यदि व्यक्तिगत रूप से राजीव गांधी को मिला है, तो कुछ अर्थों में देश को भी अवश्य ही प्राप्त हुआ है। चीन और पाकिस्तान की यात्राओं की सफलता का दारोमदार इसी बात पर निर्भर है कि इनसे दोनों (राजीव गांधी व देश) को मिलने वाले लाभ का अनुपात समुचित, समीचीन और सार्थक हो। सरकार और मीडिया भले ही इसको कितना ही क्यों न उछालें और एक नयी उपलब्धि बताकर प्रचारित करें, किंतु फिलहाल मात्र शुरुआत है। निर्णायक दौर तब होगा, जब बात असली मुद्दों पर होगी। राजीव गांधी उस समय कितनी राजनीतिक सूझबूझ, बुद्धि-विवेक, संयम और कुशल रणनीति का परिचय देंगे, यही उनकी यात्राओं की सफलता-विफलता का परिचायक होगा। विशेषकर इसलिए कि मुकाबला चीन जैसे क्रूर कूटनीतिक राष्ट्र से होगा।

कुछ आलोचक व विपक्षी नेता राजीव गांधी की उपलब्धि मात्र 'देंग' की मुलाकात बता रहे हैं, तो कुछ राजीव गांधी पर झुकने और राष्ट्रीय हितों को बेचने का आरोप लगा रहे हैं। जब इसकी चर्चा इंद्रजीत गुप्त से चली, तो वे हंसकर बोले, "न कोई बिका, न खरीदार बना। न कोई झुका न झुकाया। हां, हाथ अवश्य मिलाया।"

—रंजना कक्कड़, त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ,

राजीव गांधी की चीन यात्रा :

तिब्बतियों का भविष्य ?

चीन यात्रा के दौरान राजीव गांधी ने तिब्बत के संबंध में जो नीति अपनायी है, उस पर राजनीतिक क्षेत्रों में तो मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन भारत में रह रहे तिब्बतियों ने इस नीति की कटु आलोचना की है। राजीव गांधी ने जो तिब्बत नीति अपनायी है, क्या वह पंडित नेहरू द्वारा निर्धारित नीति से अलग है? प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बाद तिब्बत-नीति का जायजा :

FOR PEACE & HUMAN UNITY

हमारे साथ विश्वासघात हुआ है : नयी दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए तिब्बती

तिब्बत के भविष्य के बारे में राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान कोई सार्थक सुझाव मिलने की उम्मीद है या नहीं, इस सवाल पर दलाई लामा ने श्री गांधी की चीन यात्रा सें पूर्व 'माया' से कहा था, "यह प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और मैं नहीं जानता कि इससे क्या हासिल होगा?" कदाचित दलाई लामा को इस बात का पूर्वाभास था कि भारत-चीन वार्ता से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन चीन की यात्रा के दौरान बातचीत में न सिर्फ तिब्बत के मुद्दे को भुला दिया गया, बल्कि प्रधानमंत्री ने इसे चीन का आंतरिक मामला बताकर इसे पूरी तरह अनदेखा भी कर दिया। तिब्बती लोगों के लिए प्रधानमंत्री का यह बयान कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और भारत अपनी भूमि से किसी प्रकार की चीन- विरोधी राजनीतिक कार्रवाई नहीं होने देगा, सीजर की पीठ में ब्रूटस द्वारा भोंकी गयी कटार से कम नहीं था।

राजीव गांधी की चीन यात्रा समाप्ति के बाद उनका विमान पालम (दिल्ली) में जैसे ही उतरा भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रवक्ता ने तिब्बत संबंधी उनके (राजीव गांधी) रुख को अस्वीकार कर दिया। प्रवक्ता ने शिमला में जारी एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान पं० जवाहरलाल नेहरू की तिब्बत के प्रति नीति से बिलकुल अलग है। चीन यात्रा के दौरान राजीव गांधी ने कहा है कि तिब्बत चीन का भीतरी मसला है। धर्मशाला स्थित तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रवक्ता ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि १९४७ में तिब्बत ने एक स्वतंत्र राज्य की हैसियत से एशिया शांति सम्मेलन में भाग लिया था। पंडित नेहरू ने ही उस सम्मेलन में तिब्बत को आमंत्रित भी किया था।

तिब्बतियों में असंतोष : चीन यात्रा के दौरान तिब्बत के मसले पर राजीव गांधी का बदला हुआ रुख जानकर तिब्बती लोगों को लगा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। राजीव गांधी के रुख पर प्रतिक्रियास्वरूप तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ल्हासांग सेरिंग कहते हैं, "हमारे साथ दूसरी बार विश्वासघात हुआ है। नेहरू ने पहले तिब्बत को चीन के हाथों बेच डाला था और अब राजीव ने हम जैसे कुछ लोगों को बेच दिया है जो तिब्बत के बाहर शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी मौत हो रही है। खैर, अब भारत को ऐसे जख्म के साथ रहना पड़ेगा जो ३२०० किलोमीटर लंबा है।"

१९५९ में हुए विद्रोह के बाद अपना घर-बार छोड़कर यहां आये तिब्बती-शरणार्थियों की मदद करके भारत ने जो सहानुभूति हासिल की थी, उसे इस एक बयान ने धो डाला है। सेरिंग के अनुसार तिब्बती लोगों को भारत के इस विश्वासघात से गहरा दुख पहुंचा है, क्योंकि राजीव ने ऐसे मौके पर रुख बदला है, जब विश्व जनमत धीरे-धीरे तिब्बत के पक्ष में आ रहा था। तिब्बत में मानवाधिकारों की बहाली के मामले पर अनेक पश्चिमी देशों की राजनीतिक सहानुभूति बढ़ने लगी थी। अमरीकी संसद के अलावा पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन और अन्य देशों की संसदों ने भी चीन से तिब्बत में स्थिति सुधारने की मांग की थी।

भारत का यह बदला हुआ रुख जनवरी १९८९ में जेनेवा में होनेवाली दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीनी नेताओं की बातचीत के लिए भी बहुत महत्व रखता है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो० एमएल सोढ़ी कहते हैं, "जिस तरह रूस की अफगानिस्तान और अमरीका की वियतनाम से वापसी की मांग की गयी थी, उसी तरह राजीव गांधी को भी तिब्बत से चीन की वापसी और वहां बेहतर समाज बनाने में मदद देने की मांग करनी चाहिए थी। जैसे वे नामीबिया में हो रहे नरसंहार की बात करते हैं, वैसे ही उन्हें तिब्बत में हो रहे नरसंहार के मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए थी। ऐसा होने से जेनेवा वार्ता पर बहुत अच्छा असर पड़ता। इसके विपरीत उनके इस बयान से, तो किसी को भी अपनी मनमानी करने की प्रेरणा मिलेगी।" वे आगे चेतावनी के अंदाज में कहते हैं, "इस गलती का खमियाजा हमें किसी दिन बड़ी दुर्घटना के रूप में भुगतना होगा।" वैसे,

राजीव गांधी के रुख पर प्रतिक्रियास्वरूप तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ल्हासांग सेरिंग कहते हैं, "हमारे साथ दूसरी बार विश्वासघात हुआ है। नेहरू ने पहले तिब्बत को चीन के हाथों बेच डाला था और अब राजीव ने हम जैसे कुछ लोगों को बेच दिया है जो तिब्बत के बाहर शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी मौत हो रही है। खैर, अब भारत को ऐसे जख्म के साथ रहना पड़ेगा जो ३२०० किलोमीटर लंबा है।"

आजकल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष देंग जियाओ पिंग के उदार गुट पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वे तिब्बत के मसले को बातचीत की जगह डंडे के जरिए सुलझायें।

इससे भी बुरी बात यह है कि दोनों देशों के दोस्ताना संबंध में सुधार की हवाई बात के अलावा राजीव गांधी चीन से कुछ ठोस हासिल करके नहीं लौटे हैं। ऐसे में स्वभावत: नाराज हुए ल्हासांग सेरिंग कहते हैं, "हमें विश्वस्त सूत्रों से पता था कि यह पूरा दौरा और ये सारा खेल पहले से बनी योजना का अंग है। आप देखेंगे कि अगले चुनाव के पहले राजीव गांधी चीन से कुछ इलाके ले-देकर एक समझौता कर लेंगे और इसे अपनी विदेश नीति की बड़ी सफलता बताकर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। यह एक पूर्वनियोजित समझौता है, जिसमें उनको चीन से मदद मिलेगी।" अगर उनके निष्कर्षों को 'दूर की कौड़ी लाना' भी मान लिया जाये, तो भी राजीव गांधी और उनके सलाहकारों को इस दौरे की अनुकूलता सिद्ध करने में मुश्किल होगी, क्योंकि नयी दिल्ली और पीकिंग में चली अधिकारी स्तर की बातचीत के आठ दौर में भी कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हो पायी है।

पांच सूत्री कार्यक्रम : चीनी अधिकारियों से १९८२ में बातचीत के समय भी दलाई लामा के प्रतिनिधियों का रुख प्रतिरक्षात्मक ही था। दरअसल, तिब्बत का मसला दलाई लामा की निजी हैसियत तय करने की कसौटी बन गया था। सितंबर, १९८७ में दलाई लामा ने तिब्बत में शांति और मानवाधिकारों की बहाली के लिए अपना पांच सूत्री कार्यक्रम चीन के समक्ष रखा था। लेकिन चीन ने ज्यादतियां और हिंसा बढ़ाकर ही इसका जवाब दिया। अभी हाल में १० सितंबर को तिब्बती प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाकर २० बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक अनुमान के अनुसार १९५९ के उपद्रवों के बाद से तिब्बत में करीब ४००,००० लोग मारे जा चुके हैं और अनगिनत लोगों ने जेलों में दम तोड़ा है।

लेकिन जिस चीज से तिब्बती अधिक परेशान हुए और दलाई लामा को भी कड़े बयान देने पर बाध्य होना पड़ा, वह था, तिब्बत के इलाके में बड़ी संख्या में चीनी नागरिकों का बसते जाना। ऐसा ही, वहां तिब्बती संस्कृति की जगह चीनी संस्कृति लादने और तिब्बतियों को उनकी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनाने के लिए किया गया। अपनी संस्कृति पर मंडराते खतरे को भांपते हुए दलाई लामा ने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि चोल्का सुम के नाम से विख्यात तिब्बत (जिसमें यू-त्सांग, खाम और आमदो प्रांत शामिल हैं) को लोकतांत्रिक तरीके से शासित राजनीतिक क्षेत्र बनाया जाये और चीन लोकतांत्रिक तरीके से शासित तिब्बत के विदेशी मामलों का कर्ता-धर्ता बना रहे।

दुनियाभर में उनके इस प्रस्ताव पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, पर बहुसंख्यक तिब्बती लोगों ने उनके बयान पर चिंता जाहिर की। चीन ने तो प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। उसकी प्रतिक्रिया एकदम तीखी थी। ल्हासांग सेरिंग कहते हैं, "कशांग (तिब्बती मंत्रिमंडल) को चीन के साथ हेलमेल पर पाबंदी लगानी चाहिए। मैं उस पर भरोसा करके अपना जीवन उसके हवाले नहीं कर सकता। चीनियों को तो पीठ में छुरा भोंकने की आदत है।" उनका कहना है कि तिब्बती लोगों का वजूद पूर्ण स्वतत्रता मिलने पर ही बाकी रह सकता है और वे इससे कम पर राजी नहीं हो सकते। दलाई लामा ने भी 'माया' से भेंट के दौरान अपने प्रस्ताव के विरोध की बात स्वीकार की, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी तो नहीं है।

भारतीय नजरिया : चीन-तिब्बत विवाद के बारे में भारत का नजरिया यही है कि १९५० में तिब्बत पर हुए चीनी हमले का नुकसान भारत को भी हुआ था। इससे न केवल १९१४ की तिब्बत से हुई संधि के तहत होने वाले व्यापार का नुकसान हुआ, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति का भी भारत शिकार हो गया। प्रो० सोढ़ी के अनुसार, "तिब्बत पर चीनी हमले के पहले भारत का किसी भी पड़ोसी देश की सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं था।" भारत और चीन के बीच से तिब्बत का 'अस्तित्व' खतम होने के बाद ही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हुए। भारत और तिब्बत (जो अब चीन के नियंत्रण में है) के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को लेकर ही असली विवाद है। यह लाइन १९१४ में शिमला में भारत (ब्रिटिश शासन), तिब्बत और चीन के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद निर्धारित की गयी थी। आज चीन इस मैकमोहन लाइन को 'गैरकानूनी' और 'विदेशी साम्राज्यवादियों' का षड्यंत्र मानता है।

साक्षात्कार/दलाई लामा

तिब्बत पर चीन के स्वामित्व का अर्थ समूचे हिमालय-क्षेत्र का विनाश

माया : *तिब्बती इतने लंबे समय से उत्पीड़ित क्यों हैं, विशेषकर चीनी-अनुभव के संदर्भ में?*

दलाई लामा : बौद्ध मतावलंबी का सरलतम तरीका अपने पुराने कर्मों को दोषी ठहराना है। इससे हमारी दुर्भावना में कमी आयी है। दुर्भावना से चीन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टे हमारा मानसिक सुख-चैन छिन जायेगा। चीनी तिब्बती राष्ट्र व संस्कृति के विनाशक रहे हैं। वे लोभी और विस्तारवादी हैं। मैं अपनी पिछली नस्लों को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। वे तिब्बत के भीतर व बाहर के संसार की घटनाओं से पूरी तरह अलग-थलग बने रहे। चौथे दशक में जब भारत ने आजादी हासिल की, तो तिब्बत सरकार ने अपनी एक आंख बंद रखी और उसकी दूसरी आंख साफ-साफ देखने में अक्षम रही (हंसते हैं)।

माया : *क्या आप इस तथ्य से संतुष्ट हो गये हैं कि चीनी तिब्बत में प्रभावी मुद्दा बने रहेंगे? क्या इसीलिए आपने स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि चीन के हाथ में विदेश नीति रहनी चाहिए और तिब्बतियों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए?*

लामा : कम्युनिस्ट चीन के तिब्बत पर अधिकार के साथ ही आबादी के स्थानांतरण की समस्या शुरू हो गयी। हमारी गणना के अनुसार वहां तिब्बती आबादी ६० लाख है और चीनी आबादी ७० लाख है। तिब्बत में हाल में तीन महीने रहकर आनेवाले एक अंग्रेज ने मुझे बताया कि लगातार चीनी आबादी के लिए हर सप्ताह नये मकान आदि बन रहे हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन बसों में भरकर चीनी उत्तरी तिब्बत मार्ग से लाये जा रहे हैं। यदि यह स्थिति दस साल बनी रही, तो तिब्बती अल्पसंख्यक हो जायेंगे। तिब्बत यदि सचमुच चीनी भूमि बन गया, तो समूचे हिमालय क्षेत्र में मूलगामी परिवर्तन हो जायेगा। तिब्बती अपनी स्वतंत्रता के लिए

जोर दे रहे हैं और चीन को यह मंजूर नहीं। ऐसी स्थिति में लगातार चीन के अधीन रहना असंभव है, क्योंकि जनता उत्पीड़ित होगी। यह भी सच है कि आजादी हासिल करना बेहद कठिन है। इसलिए तिब्बती जनता के स्वतंत्र प्रवक्ता के रूप में मैंने मध्य मार्ग की सलाह देना उचित समझा, जिससे उत्पीड़न से मुक्ति मिले और आबादी का स्थानांतरण रुके। इसीलिए मैंने स्ट्रासबर्ग प्रस्ताव पेश किया है।

माया: ***क्या आपके इस प्रस्ताव का तिब्बतियों ने विरोध किया है?***

लामा: हां, तिब्बत में और बाहर भी। अनेक लोगों ने आरोप लगाया कि दलाई लामा ने तिब्बत को बेच दिया है।

माया: ***आपके विचार से तिब्बत के बारे में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए?***

लामा: भारत को हर हालत में तिब्बत की अस्मिता (पहचान) की रक्षा करनी चाहिए। पंडित नेहरू ने संसद में १९५९ में कहा था कि तिब्बत का भविष्य अंततः तिब्बती तय करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें न केवल भारत की नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि उसका अपना हित भी है।

माया: ***चीन से समझौते की स्थिति में क्या आप भारत में भलीभांति स्थापित तिब्बतियों को तिब्बत वापस ले जायेंगे?***

लामा: नहीं, यह उनके (भारत स्थित तिब्बतियों के) सोचने की बात है। वे अपनी इच्छा से आये थे। कोई संतोषजनक समझौता होने पर उनमें से अधिकांश स्वदेश लौट सकते हैं। कुछ यहां रह भी सकते हैं।

माया: ***क्या आप समझते हैं कि तिब्बती भारतीय समाज में घुलने-मिलने में सफल रहे हैं?***

लामा: सभी तिब्बती प्रवासियों के स्थानीय लोगों से बड़े मधुर व अंतरंग संबंध हैं। कभी-कभी स्थानीय राजनीतिक कुछ समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तिब्बतियों ने हिंदी तथा अन्य भाषाएं बोलना भी शुरू कर दिया है।

माया: ***क्या आप अंतरजातीय विवाहों को भी प्रोत्साहित करेंगे?***

लामा: हमारे यहां ऐसे विवाहों को रोकने का कानून नहीं है। किंतु हम अपनी पहचान के लिए चिंतित हैं। हम राजनीतिक शरणार्थी हैं, जिन्हें अपना संघर्ष चलाना है। साथ ही तिब्बत के भीतर समुचित प्रभाव पैदा करना है। यदि हमने अपनी पहचान खो दी और भारतीयों में हिल-मिल गये, तो तिब्बत में हमारे अपने लोग क्या सोचेंगे? भारत ही नहीं, हर जगह हमारे लोग तिब्बती पहचान बनाये रखने के लिए प्रयासरत हैं। ■

आज तीन इलाकों में भारत और चीन आमने-सामने हैं—पश्चिमी क्षेत्र (लद्दाख), मध्य क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश और उप्र) तथा पूर्वी क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश)। १९५७ में चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में सिंक्यांग-तिब्बत राजमार्ग खोला। यह रास्ता अकसाई चिन के भारतीय क्षेत्र तक आता है और चीन ने लद्दाख क्षेत्र में १४५०० वर्गमील भारतीय क्षेत्र पर गैरकानूनी कब्जा कर लिया है। पूर्वी क्षेत्र में चीन अरुणाचल प्रदेश के ३३०० वर्गमील क्षेत्र पर अपना दावा करता है। प्रो० सोढ़ी कहते हैं, "चीन मैकमोहन लाइन को गलत बताकर अपना दावा पेश करता है। अकसाई चीन के इलाके पर अपना कब्जा बनाये रखने के लिए चीन की यह कुटिल चाल है।" ऐसे में अपने इलाके वापस पाने की भारतीय कोशिश में किसी तरह की जल्दबाजी या कमजोरी नहीं होनी चाहिए। फिर तिब्बती लोग भी हमारे दावे के पक्ष में हैं।"

तिब्बतियों का कहना है कि सीमा विवाद के मामले में भारत सीधे चीन से बात न करके तिब्बत सरकार से बात करे। दलाई लामा ने बार-बार भारत सरकार से कहा है कि भारत और तिब्बत के बीच कोई सीमा विवाद नहीं होगा, अगर भारत ने हिम्मत दिखाकर तिब्बतियों के स्वशासन के अधिकार को मान्यता दे दी।

लेकिन वास्तविकताएं ऐसे काल्पनिक और महत्वाकांक्षी सोच को आगे नहीं बढ़ने देतीं। भारत की बुनियादी चिंता भी सीमा पर होनेवाले अपने प्रतिरक्षा खर्च में कटौती करने की ही है। यह माना जाता है कि भारत प्रतिदिन चीनी सीमा पर प्रतिरक्षा में तीन करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और यह खर्च उठाना उसके लिए बहुत महंगा है।

लेकिन प्रो० सोढ़ी चेतावनी देते हैं, "चीन के साथ किसी भी समझौते का मतलब देश के दीर्घकालिक हितों और सुरक्षा संबंधी बातों की उपेक्षा करना नहीं होना चाहिए।" भारत के नीति निर्माताओं को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या दोनों देशों के संबंध सामान्य हो जाने के बाद वे सीमा पर सुरक्षा का खर्च समाप्त कर सकते हैं। पहले के अनुभवों और चीन की महत्वाकांक्षी विस्तारवादी नीति को देखते हुए भारत कभी भी उस सीमा से आंख मूंदकर आराम से नहीं बैठ सकेगा।

स्थिति यह है कि आज भी चीन के अधिकृत नक्शों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत से अलग ही दिखाया जा रहा है। राजीव गांधी और उनके सलाहकार इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? क्या वे हाल में ही (१९८६) अरुणाचल के सुमदरोंग चु दर्रे में हुई घुसपैठ को भूल गये हैं। जैसा कि प्रो० सोढ़ी कहते हैं, "माओवाद से लेकर मौजूदा देंगवाद तक चीन की सैनिक और विस्तारवादी नीति बदली नहीं है।"

तिब्बत में बढ़ती चीनी सैनिक संख्या भी चिंता का एक बड़ा कारण है। अनुमान है कि चीन ने तिब्बत में पांच लाख सशस्त्र सैनिक रख छोड़े हैं। वहां उन्होंने नौसैनिक हवाई अड्डे, करीब १५ राडार स्टेशन और तीन परमाणु अड्डे बना लिये हैं। इस बात की पक्की सूचना है कि चीन ने वहां ऐसे मिसाइल लगा रखे हैं जिनका निशाना भारत और सोवियत संघ के प्रमुख शहर हैं। ल्हासा से ३२० किमी उत्तर में स्थित नागचु सैनिक अड्डे को और आधुनिक बनाया जा रहा है। जिससे वहां अन्य भारतीय शहरों सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के नगरों को लक्ष्य बनाकर परमाणु मिसाइलें लगायी जा सकें। ऐसी स्थिति में क्या तिब्बत को चीन के हवाले करना मूर्खता नहीं है?

कुछ राजनीतिक पंडितों का तो मानना है कि तिब्बती तुरुप के पत्ते को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत के पास यही समय सबसे अनुकूल था। इससे तिब्बती लोगों की समुचित मांगों का समर्थन हो जाता और दलाई लामा के प्रस्ताव को मानने के लिए चीन पर दबाव भी पड़ता। लेकिन भारत ने यह मौका गंवा दिया। इतना ही नहीं अफवाह है कि भारत में रहनेवाले ९५००० तिब्बती शरणार्थियों के तिब्बत में पुनर्वास के लिए भारत और चीन में समझौता भी हो गया है।

कुछ राजनीतिक पंडितों का तो मानना है कि तिब्बती तुरुप के पत्ते को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत के पास यही समय सबसे अनुकूल था। इससे तिब्बती लोगों की समुचित मांगों का समर्थन हो जाता और दलाई लामा के प्रस्ताव को मानने के लिए चीन पर दबाव भी पड़ता। लेकिन भारत ने यह मौका गंवा दिया। इतना ही नहीं अफवाह है कि भारत में रहनेवाले ९५००० तिब्बती शरणार्थियों के तिब्बत में पुनर्वास के लिए भारत और चीन में समझौता भी हो गया है। इससे भारत को शरणार्थियों के बढ़ते बोझ से कुछ राहत मिलेगी। तो क्या यही भारत के नये रुख का प्रमुख कारण है? अभी तो यही लग रहा है।

इन सचाइयों के अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दलाई लामा की इस बात में बहुत दम है कि सदियों से पड़ोसी रहे तिब्बत के प्रति भारत का कुछ नैतिक दायित्व भी है। अभी तो सिर्फ यह उम्मीद की जा सकती है कि राजीव गांधी इस दायित्व से मुंह नहीं मोड़ेंगे और अधिक क्षति होने से पूर्व ही स्थिति को सही दिशा प्रदान करेंगे।

—पद्मा शास्त्री

मनोहर कहानियाँ

अतिरिक्तांक

होली विशेषांक

मुख्य आकर्षण

अग्नि-परीक्षा

मोधिया जन जाति की परम्पराओं से जुड़ी हुई एक ऐसी नारी की मर्मस्पर्शी कहानी, जो अग्नि-परीक्षा में खरी उतरकर निष्पाप सिद्ध हुई।

प्रतिशोध

महाराजा सवाई जयसिंह के जीवन से जुड़ी हुई रोमांचक ऐतिहासिक कथा, जिसमें जयसिंह की रानी ने ही खून का बदला खून से लिया।

विदेशिनी

बेल्जियम से प्रेमी के साथ भारत भागने वाली युवती एक बार धोखे की शिकार बनी तो बराबर बनती ही गयी और अंत में जिंदगी का उजाला मिला भी तो अधिक दिन जी न सकी। नारी-व्यथा की मर्मस्पर्शी कथा

मुझे जीने दो

आत्मा के उद्बोधन पर अपराध-पथ छोड़कर नेक इंसान बनने वाले व्यक्ति की अद्भुत प्रेरक कथा श्रीकांत सिनकर की कलम से।

साथ में अन्य रोमांचक, रोचक और हृदयग्राही कथाएं भी

१५ फरवरी, १९८९ तक प्रकाश्य

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित करायें

स्थानीय निकाय चुनाव

दलों को निर्दलों की शिकस्त

१७ वर्षों में २६ बार वायदे और ऐलान टालने के बाद उत्तर प्रदेश में हाल ही हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने सभी दलों— खासकर कांग्रेस— के दावों को दिवालिया साबित कर दिया है। कैसे हुआ यह ?

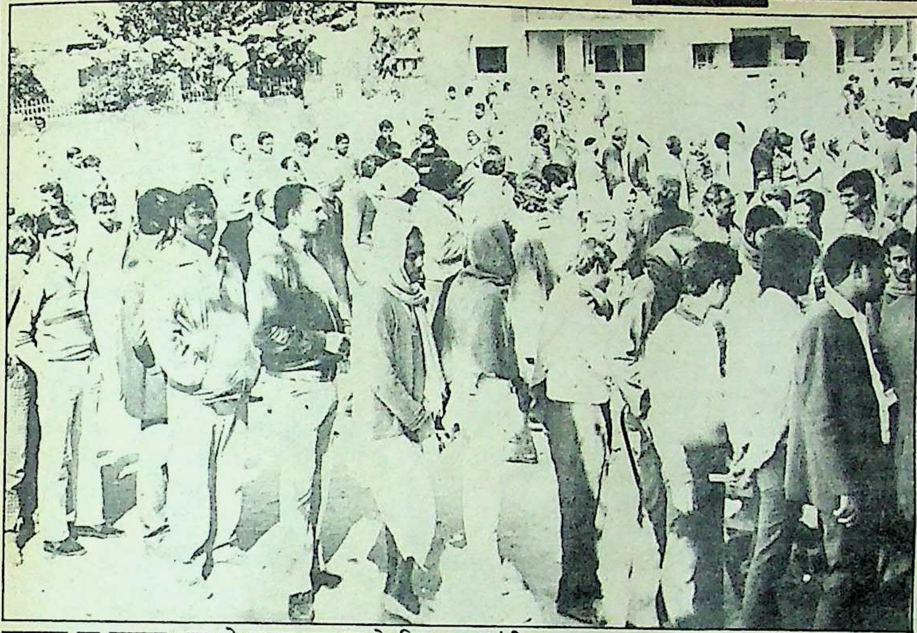

मतदाता का मतलब : बूथ के बाहर मतदान के लिए कतारबंदी

उत्तर प्रदेश में १७ वर्ष बाद हुए 'स्थानीय निकाय चुनावों' ने साबित कर दिया है कि शहरी मतदाताओं में राजनीतिक दलों की साख घटी है। यही वजह है कि इस चुनाव में तकरीबन ८३ प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। अब इन्हीं निर्दलीयों को अपना-अपना जताने में सत्तापक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों में होड़ लगी है। इन चुनावों ने सत्तापक्ष तथा अन्य राजनीतिक दलों को अल्पसंख्यकों और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का भी संकेत देकर चिन्तित कर दिया है। इस गठबंधन का ही परिणाम है कि पंचायत और ब्लाक प्रमुखों की अपेक्षा निकाय चुनावों में अल्पसंख्यकों ने रिकार्ड जीत हासिल की है।

प्रदेश में ८ नगर महापालिकाओं समेत २२४ नगर पालिकायें, ४१८ टाउन एरिया और २० नोटीफाइड एरिया हैं। इनके लिए दो चरणों में चुनाव कराये गये। पहले चरण में १ लाख तक की आबादी वाली १९५ नगर पालिकाओं, ४१२ टाउन एरिया और २० नोटीफाइड एरिया कमेटियों के चुनाव १२ नवंबर '८८ को तथा दूसरे चरण में १० जनवरी '८९ को ६ नगर महापालिकाओं, एक लाख से अधिक आबादी वाली २६ नगर पालिकाओं, और साथ ही ४ टाउन एरिया कमेटियों के चुनाव हुए। शेष में २ नगर महापालिकाओं, ३ नगर पालिकाओं के साथ-साथ २ टाउन एरिया कमेटियों में विभिन्न कारणों से नियत तिथि पर चुनाव नहीं हो सके। नगर महापालिकाओं में लखनऊ में परिसीमन पूर्ण न होने पर तथा इलाहाबाद में कुंभ के चलते चुनाव की तिथियां टाल दी गयीं। २ नगर पालिकाओं मवाना (मेरठ), नवाबगंज (गोंडा) तथा दो टाउन एरिया कमेटियों गहमर (गाजीपुर) और ऐलम (मुजफ्फरनगर) के चुनाव उच्च न्यायालय के स्थगन-आदेशों के कारण नहीं हो सके।

अदालत का आदेश : स्थानीय निकायों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी संविधान में उल्लिखित है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के सत्ताधारियों ने १७ वर्ष तक लोकतंत्र के सैद्धांतिक प्रावधानों की अवमानना की। आखिरकार ये चुनाव कराने में उच्च न्यायालय के एक आदेश के क्रियान्वयन की भी मजबूरी रही। लखनऊ के वकील सीताराम द्विवेदी ने २ दिसंबर, १९८६ को उच्च न्यायालय में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए सरकार को पार्टी बनाते हुए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र माथुर तथा सगीर अहमद ने १४ मई १९८७ को दियें अपने निर्णय में सरकार को निर्देश दिया था कि स्थानीय निकायों के चुनाव दिसम्बर ८७ तक करा दिये जायें। सरकार की ओर से कई दिक्कतों का जिक्र करते हुए इस निर्धारित समय में चुनाव न करा सकने संबंधी एक प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने तर्कसंगत न मानते हुए खारिज कर दिया था।

१९७१ के बाद लगभग २७ बार निकायों के चुनाव कराने की घोषणायें की गयीं। चुनाव के लिए सत्तापक्ष पर दोषारोपण करने वाला विपक्ष भी सत्ता पाकर इस चुनाव को भुला बैठा था। प्रदेश में जनता शासन काल में स्वायत्तशासन मंत्रियों (सत्यप्रकाश मालवीय, गणेशदत्त वाजपेयी तथा राम आधार पांडेय) ने अपने-अपने कार्यकाल में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का वायदा कर जनता को खूब भुलावा दिया था। हेमवती नंदन बहुगुणा का लोकदल इस चुनाव की मांग को लेकर प्रदेश में कई बार मुखर हुआ था। यह 'नीतिविहीन राजनीति' का ही नतीजा था कि स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के बजाय उन पर प्रशासक थोपने का काम बहुगुणा ने ही प्रदेश में अपने मुख्यमंत्रित्व-काल में किया था। तब से अब तक कई मुख्यमंत्री आये-गये। सबने निकाय चुनाव कराने की बात कही, लेकिन अंततः छठें मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी को ही यह जिम्मेदारी निभानी पड़ी।

अपने-अपने दावे : इस चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी दलीय आधार पर चुनाव लड़ी। उसने इस चुनाव के लिए बाकायदा घोषणापत्र जारी किया। चाहते तो अन्य दल भी यही थे कि वे अपने उम्मीदवार खड़ा करें, लेकिन निकायों के ६६० अध्यक्षों तथा करीब १० हजार सदस्यों के लिए उम्मीदवारों का चयन शैतान की आंत नापने जैसा काम था। चुनाव की गहमागहमी शुरू होते ही उम्मीदवारों में अपनी-अपनी पार्टी का ठप्पा लेने की होड़ लग गयी थी। प्रदेश इंका अध्यक्ष बलराम सिंह यादव ने फैसला किया कि पार्टी सर्वसम्मत उम्मीदवार को ही टिकट देगी। नतीजा यह हुआ कि पार्टी के नगर और जिला स्तर के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों के बीच उखाड़-पछाड़ शुरू हो गयी। पहले से ही स्थापित हो चली जिलों में गुटबाजी इस चुनाव में और भी मुखर हो गयी। न्यूनाधिक अन्य दलों की भी यही स्थिति रही। एक-एक स्थान पर एक-एक दल के कई-कई दावेदार मैदान में उतरे और आपस में लड़े-कटे। पार्टी-आधार पर चुनाव न लड़ने की इंका सहित अन्य विपक्षी दलों की नीति का असली उद्देश्य था, अपनी साख बनाये रखना। जीते हुए लोगों को अपनी पार्टी का बताकर पार्टी के जनाधार को दर्शाया जा सकता है। हुआ भी यही। अब इंका समेत अन्य विपक्षी दल निर्दलीय जीते हुए लोगों को अपना बताने लगे हैं। यदि इनके दावों पर नजर डाली

जाये, तो निकायों के इन जीते हुए पदाधिकारियों की संख्या से वास्तविक संख्या कई गुनी ज्यादा बैठती है। एकमात्र भाजपा ने दलीय आधार पर चुनाव लड़ा, तो उसके जीते हुए प्रत्याशियों को गिन लिया गया। भाजपा के कुल उम्मीदवारों में लगभग १८ प्रतिशत जीते। पार्टी का दावा है कि हमारे उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत ३० से अधिक है। इंका ने सर्वसम्मति के आधार पर चुनाव के पहले चरण में १०० प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इनमें जीते तो केवल २७, लेकिन इंका का दावा है कि २७० निकायों के अध्यक्ष पदों पर उसके उम्मीदवार जीते हैं। दूसरे चरण में भी इंका अपने को जीत के प्रथम स्थान पर मानती है। कमोवेश ऐसे ही बढ़े-चढ़े दावे अन्य विपक्षी दलों के भी हैं।

इंका को झटका : पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का मोटे तौर पर आकलन किया जाये, तो स्थिति थोड़ी-बहुत स्पष्ट होती है। प्रदेश के पूर्वी जिलों में इंका को झटका लगा है। जनता दल के जनतापार्टी घटक ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी साख बनाये रखी। लोकदल के भी जीते उम्मीदवारों में ज्यादातर इसी क्षेत्र के हैं। इंका को कई जगहों पर अपनी प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई में मुंहकी खानी पड़ी। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की करीबी केंद्रीय संसदीय राज्यमंत्री शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज (फर्रुखाबाद) में इंका समर्थित उम्मीदवार श्यामस्वरूप मिश्र भाजपा के केशव दास टंडन से बुरी तरह मात खा गये। मिश्र को जिताने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री बिहारी लाल दोहरे शुरू से ही कन्नौज में अपनी चौपाल जमाये हुए थे। श्रीमती दीक्षित ने अपने सिपहसालार पीएन कपूर को मिश्र को जिताने में लगा रखा था। बावजूद इस कोशिश के मिश्र तीसरे नंबर पर रहे। गढ़वाल मंडल में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री और प्रदेश के पयर्टन राज्यमंत्री गुलाब सिंह की लामबंदी खुलकर सामने आयी। दोनों ने अपने-अपने समर्थक मैदान में उतारे, जिनमें अधिकांश हार गये। देहरादून में ब्लाक प्रमुखों के चुनावों में इंका को सौ फीसदी सफलता मिली थी, लेकिन पालिका चुनावों में स्थिति पलट गयी। ऋषिकेश नगरपालिका के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वीरेंद्र ने इंका के नगर अध्यक्ष हरिमोहन गुलाटी तथा ब्रह्मदत्त समर्थक मदनमोहन शर्मा को पराजित किया। विकास नगर में जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गोविंद राम ध्यानी हार गये। मसूरी में भी नगर कांग्रेस अध्यक्ष देवराज कपूर को हार का मुंह देखना पड़ा। गोरखपुर मंडल में भी इंका समर्थित प्रत्याशी बुरी तरह हारे। महमूदाबाद (सीतापुर) में प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री अम्मार रिजवी की लहुरी (छोटे भाई की पत्नी) अजीज फातिमा अपने जेठ की रहनुमाई और सतत प्रयत्न के बावजूद जीत नहीं सकीं। इटावा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव के मुकाबले जनतादल के प्रदेश में शक्तिशाली नेता मुलायम सिंह के समर्थित प्रत्याशी बाजी मार ले गये। भाजपा ने जीत का सर्वाधिक प्रतिशत बनारस, आगरा और मिर्जापुर में दर्शाया। लेकिन इसके प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह अपने ही जिले अलीगढ़ में सिमट कर रह गये। यहां ४० सदस्यीय नगरपालिका के चुनाव में भाजपा को केवल ४ स्थानों पर ही सफलता मिल सकी। चुनाव के दूसरे चरण में तो इसके तीन-चौथाई प्रत्याशी हारे। लेकिन पार्टी का दावा है कि उसके ८५८ प्रत्याशियों में २७५ जीत गये हैं। लोकदल की स्थिंति दूसरे चरण में और भी डांवाडोल रही। इंका को जीत का ढिढोरा पीटने का एक मात्र सबब अमेठी में मिला, जहां से जनतादल के युवा तुर्क संजय सिंह ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को संसद का चुनाव लड़ने की चुनौती दे रखी है। अमेठी टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष पद पर इंका ने कब्जा किया, जबकि संजय सिंह के उम्मीदवार को अपनी जमानत तक गंवानी पड़ी।

सरकार की मार: डा० बालाजी पाठक (इनसेट) की शवयात्रा

धन, ताकत का खेल: कानपुर के गोविंद नगर वार्ड से पंजाबी वर्ग के रहनुमा [illegible] देशराज के नाती अजय कपूर चुनाव लडे और पैसे का खेल खेला। उनके समर्थन में आतंकवादियों द्वारा मारे गये विधायक स्व० बिलायती राम कत्याल की विधवा ने घर-घर जाकर वोट मांगे। मेरठ में शास्त्री नगर वार्ड से जिले के प्रमुख उद्योगपति अरुण जैन तथा वार्ड नंबर ७ से उत्तर प्रदेश ट्रक आपरेटर्स यूनियन के महासचिव जगन्नाथ तथा सर्वोदय फाइनेंस कंपनी के मालिक सतपाल अपने-अपने धनबल के साथ चुनाव लड़े। इस चुनाव ने वेश्याओं में भी अपने मताधिकार के प्रति जागरुकता पैदा कर दी। मेरठ के कबाड़ी बाजार में स्थित ४२ कोठों की ५०० वेश्याओं की ओर से 'तवायफ संगीत समिति' की अध्यक्ष लौंगश्री ने ऐलान कर दिया कि वेश्याओं की मांग पूरी करानेवाले को ही तरजीह दी जायेगी। उनकी मांगों में कोठों का वक्त रात १० बजे की जगह ११ बजे तक रखने तथा पुलिस के छापों से निजात दिलाने की बात शामिल थी।

निकाय चुनावों में प्रदेश के एक दर्जन जिलों में हुई हिंसक वारदातों में लगभग १०० लोग गंभीर

पैशाचिकता के खिलाफ: लाठी चार्ज के विरुद्ध वाराणसी में प्रदर्शन

रूप से घायल हुए। मतपत्रों की लूट, बूथ पर कब्जा तथा मतपेटियां छीनी जाने की कई घटनाएं हुईं। बनारस में भाजपा नेता बालाजी पाठक की हिंसक वारदात में मौत हो गयी। इन घटनाओं के कारण कई जगहों पर चुनाव रद्द करना पड़ा। दोबारा हुए मतदान में भी इसकी पुनरावृत्ति हुई। ये घटनाएं इस बात की द्योतक हैं कि राजनीति में अपराधी तत्वों का कितना समावेश हो चुका है! पंचायती चुनावों और ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में भारी संख्या में अपराधियों ने अपनी जीत दर्ज करा दी थी। अब निकाय चुनावों में उनके हौसले बुलंद होना स्वाभाविक ही है। सफदर हाशमी भी इन्हीं चुनावों में हिंसा के शिकार बने।

बेचारे निकाय: इतने समय तक नौकरशाहों के कब्जे में रहे इन निकायों में वित्तीय संसाधनों की कमी, अधिष्ठान-व्यय में लगातार वृद्धि, करों के पुनर्निर्धारण में लापरवाही, वसूली में ढिलाई, आय और व्यय में अंतर, वित्तीय अनियमितताओं का आलम आदि ऐसे पहलू हैं, जिनके कारण ये निकाय सरकारी अनुदान पर ही निर्भर हैं। स्थानीय निकायों की दशा सुधारने के लिए कई बार सरकारी समितियां बनायी गयीं। उनके सुझाव आये, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। सबसे पहले १९६३ में मंत्रियों की एक समिति बनी, जिसके सुझाव फाइल तक सीमित रह गये। १९७४ में राज्य कराधान समिति ने संपत्ति और सेवाकरों में वृद्धि करने के सुझाव दिये थे। १९८० में भी ऐसी ही एक समिति ने करों में वृद्धि का प्रतिशत तय किया था। डाक्टर टीएस पपोला की अध्यक्षता में बनी कराधान समिति ने १९८६ में निकायों की दशा सुधारने के सुझाव देते हुए वृत्ति कर लगाये जाने की राय व्यक्त की थी। इन समितियों के सुझावों पर नौकरशाहों ने अमल नहीं किया। हालत इस हद तक बदतर है कि सरकार से सड़क-अनुदान के नाम पर मिलने वाली रकम का एक बड़ा भाग कर्मचारियों के वेतन में समाहित हो रहा है। घोटालों का स्तर यह है कि कई निकायों में कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन अनुदान तक का दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में निकायों की राजस्व आय का प्रमुख स्रोत अब चुंगी ही रह गया है।

वैसे भी निकायों के ऐसे हिस्सों को नौकरशाहों ने अपनी कमाई का जरिया मानकर अलग करा दिया है, जहां से राजस्व-प्राप्ति की उम्मीद की जा सकती थी। महापालिका आज तीन टुकड़ों में बंट चुकी है। प्रदेश की अफसरशाही ने बड़ी सफाई से विकास प्राधिकरण और जल संस्थान को अलग कराकर अपनी कुरसी का ठीहा ढूंढ़ लिया है। यही वजह है कि अलीगढ़, गाजियाबाद और मुरादाबाद में नगर महापालिका न होने के बावजूद वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किये गये। विकास के नाम पर गठित इन प्राधिकरणों पर काबिज नौकरशाहों की कमाऊ-कुरसियों को कौन हटा पायेगा?

छाया: मंसूर आलम

—सुरेश द्विवेदी

कांग्रेस का दावा और द्वंद्व

स्थानीय निकायों के चुनाव-परिणाम आने के बाद अब वे राजनीतिक दल, जिन्होंने दलीय आधार पर चुनाव नहीं लड़ा था, अपनी-अपनी जीत को बढ़ा-चढ़ा कर दावा पेश कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी एक सूची जारी कर अपने जीते हुए प्रत्याशियों की गिनती करायी है। इस सूची में दावा किया गया है कि इन चुनावों में ६३ प्रतिशत निर्दलीय प्रत्याशी, इंका के समर्थन पर जीते हैं। १३ जनवरी को प्रदेश इंका के महामंत्री रामनाथ मुंशी द्वारा पत्रकारों को दी गयी कांग्रेस समर्थित विजयी प्रत्याशियों की सूची में तब तक विजयी घोषित ६६० निकाय प्रत्याशियों में से ४१५ को पार्टी समर्थित दर्शाया गया है। मुंशी की यह दावेदारी कितनी सच है? उनकी सूची के अनुसार अल्मोड़ा के २४ स्थानों में से १९ पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अल्मोड़ा में निकायों के चुनाव अभी हुए ही नहीं हैं। इसी तरह इटावा में २४ स्थानों में १५ पर इंकाई उम्मीदवारों की विजय का दावा किया गया है। खास बात यह रही कि १३ जनवरी को जिस दिन मुंशी ने यह सूची जारी की, उस समय तक इटावा के २१ स्थानों के ही चुनाव परिणाम घोषित हुए थे।

चुनाव से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बलराम सिंह यादव ने दलीय आधार पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का मन बनाया था। इसमें केंद्रीय संचारमंत्री वीरबहादुर सिंह की भी रजामंदी थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इससे वीरबहादुर ने बलराम सिंह यादव के प्रति नाराजगी प्रकट की है। दूसरी ओर यादव का कहना है कि दलीय आंधार पर चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान के निर्देश पर रद्द किया गया था। वीरबहादुर सिंह का मानना है कि दलीय आधार पर चुनाव न लड़ने के कारण पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसके कारण आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं की कमी होने की संभावना है। उनका तर्क है कि पार्टी का टिकट न मिलने पर पार्टी के ही लोग आपस में लड़-भिड़ गये, जिससे आपस में ही द्वेष पैदा हो गया। दूसरे, जो विजयी हुआ वह भी अपनी जीत का श्रेय पार्टी को नहीं देना चाहता। ऐसे विजयी लोगों का मानना है कि वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव से जीते हैं।

बहरहाल, सच यह है कि कांग्रेस के दलीय आधार पर चुनाव न लड़ने के निर्णय ने कस्बाई स्तर तक पार्टी में गुटबंदी का माहौल पैदा कर दिया है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक महामंत्री का कहना है कि दलीय आधार पर चुनाव न लड़ने के निर्णय से हमें अपने कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत हैसियत का पता लग गया है।

—सु० द्वि०

इंका विधायक की हत्या

क्या रामाराव का महल ढहेगा ?

एनटी रामाराव को ऐसी आशंका नहीं है कि केंद्र आंध्र प्रदेश में कोई संकट पैदा करने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। अगर क़ांग्रेस आलाकमान अपने विधायकों को विधानसभा से इस्तीफा देने की अनुमति दे भी दे और ऐसी स्थिति में रामाराव के लिए चुनाव कराने के अलावा कोई और चारा न रह जाये, तो भी उनकी स्थिति कमजोर नहीं होगी। हां, रामाराव के मन में इस खतरे का अहसास जरूर हुआ है कि कहीं कांग्रेस अपने विधायक वागावीति मोहन रंगाराव की हत्या को हथौड़ा बनाकर तेलुगूदेशम के उस 'महल' को गिरा न दे जो उसने 'नैतिकता और क्षेत्रीय भावना' के आधार पर खड़ा किया है।

इस हत्या से पैदा हुई परेशानियों से बड़ी चतुराई से निबटते हुए रामाराव पूछते हैं, "राजीव गाधी से यह कहने से क्या फायदा कि वे अपनी पार्टी के लोगों को जाति के आधार पर आंध्र में बंटने से मना करें ?" अपने सवाल का जवाब खुद ही देते हुए वे कहते हैं, "मैं किसी एक समुदाय या जाति के लिए सरकार नही चला रहा हूं।" लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हत्या के बाद से उत्पन्न तनाव और जातीय अकड़बाजियां बढ़ती ही जा रही हैं।

दोतरफा हिंसा का अंजाम: रंगाराव, समुदायों के आधार पर लड़ाई शुरू करके तेलुगूदेशम को कमजोर करने की कांग्रेस की राजनीति के अगुवा थे। १९८८ के शुरू में प्रभावशाली 'कप्पू' जाति के लोगों को आंध्र की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का दावा करने के लिए जो 'कप्पूनाडु' आयोजित हुआ था, उसमें भी रंगाराव ही कर्ताधर्ता थे। यह सम्मेलन रामाराव द्वारा आयोजित 'महानाडु' के साल भर बाद उसी के जवाब में किया गया था। महानाडु का आयोजन रामाराव ने राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में अपना दावा मजबूत करने के लिए किया था। इस आयोजन को 'कम्मा' रंग देने का कोई मंशा नहीं था। रामाराव खुद भी 'कम्मा' जाति के हैं। आंध्र की राजनीति पर 'कम्मा' और 'रेड्डी' जाति के लोगों का प्रभुत्व रहा है, जबकि उनकी जनसंख्या क्रमश: सिर्फ ९ और ८ फीसदी ही है। २२ फीसद्री जनसंख्या वाले कप्पू अभी तक दूसरे दर्जे की भूमिका ही निभाते रहे हैं। कप्पुओं को पहले दर्जे की भूमिका दिलाने के फतवे पर जो कप्पू-विजय अभियान चला, वह वागावीति और देविनेनी परिवारों के बीच, वर्चस्व के लिए, हिंसा-प्रतिहिंसा का माध्यम बन गया। तेलुगूदेशम में कप्पू लोगों का भी कुछ प्रभाव है और अगर काग्रेस जातीय भावना भड़काकर (जैसी कि रंगाराव की हत्या के बाद रणनीति अपनायी गयी) इनका समर्थन पाने में कामयाब रही, तो इससे तेलुगूदेशम का राजनीतिक असर घटेगा।

हत्या की परिणति: तोड़-फोड़ और तबाही का निरीक्षण करते हुए एनटी रामाराव

तूल: अंत्येष्टि के समय रंगाराव के समर्थक

इस कप्पू-विजय के दोतरफा हिंसक अभियान के चौथे शिकार बने रंगाराव खुद भी कप्पू थे। २६ दिसंबर, १९८८ को उनकी हत्या के बाद जो दंगे भड़के, उनमें कम-से-कम ५० जानें गयीं (हालांकि सरकार ३४ से अधिक मौतें नही मानती) और करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटी या नष्ट कर दी गयी। इसमें अधिकांश संपत्ति 'कम्मा' समुदाय के लोगों या राज्य सरकार की थी।

इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की काली छाया तेलुगूदेशम पार्टी पर भी पड़ी। ९ तटवर्ती जिलोंके साथ रायलसीमा धीरे-धीरे उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाता दीखने लगा। तेलगांना में भी उसके आधार को अब चुनौती दी जाने का खतरा है। इसी गहमागहमी के बीच रंगाराव की विधवा, ३५ वर्षीया रत्ना कुमारी 'अपने पति के अधूरे अभियान को पूरा करने और आंदोलन की अगुवाई करने' के

लिए रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्र का दौरा करने की योजना बना रही हैं। उनका कहना है, "मेरा, उद्देश्य बदला लेना है और यही मेरे स्वर्गीय पति को मेरी श्रद्धांजलि होगी। हम भगवान का वेश धारण करने वाले हत्यारे नहीं हैं। भगवान और कानून दोषी लोगों को दंडित करेंगे। तब तक डटी-जुटी रहूंगी जब तक रामाराव अपनी गद्दी से उखाड़ न फेंके जायेंगे"। किंतु सवाल यह है कि क्या रत्ना कुमारी राज्य के एक करोड़ कप्पू लोगों की नेता बन जायेंगी, और कांग्रेस तथा तेलुगूदेशम की मौजूदा किलेबंदी को तोड़ पायेंगी?

गिरोह युद्ध : विडंबना यह है कि रंगाराव की हत्या तभी की गयी, जब वे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। १९७४ में उनके बड़े भाई राधा की हत्या कर दी गयी थी। उन्हें किसी दुकान का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था और जैसे ही वे दुकान में घुसे, उसके दरवाजे बंद कर दिये गये और उनको छुरा भोंक कर मौत के घाट उतार दिया गया। राधा की हत्या देवीनेनी राजशेखर के बड़े भाई, गांधी की हत्या से ही जुड़ी थी। दरअसल, राधा और गांधी शुरू में एक ही गुट में थे। यह गुट तेजी से प्रभावशाली हुआ था और इसका विजयवाड़ा की अनेक झोंपड़पट्टियों पर काफी प्रभाव था। ये दोनों चलासानी वेंकटरत्नम के गिरोह में थे, जो खुद इस गिरोह के सरगना पद हथियाने की लड़ाई में मारा गया था। इसी मुद्दे पर राधा और गांधी भी अलग हुए थे और फिर इनके गिरोहों की लड़ाई बहुत कुछ शिकागो के माफिया गिरोहों की लड़ाई की तरह चली थी।

लेकिन १९८५ में रंगाराव और राजशेखर के विधानसभा के लिए चुन लिये जाने के साथ ही इनकी लड़ाई ने भी राजनीतिक रूप ले लिया। रंगाराव विजयवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर जीते, तो राजशेखर कांकीपाडु से तेलुगूदेशम के टिकट पर। १ मार्च, १९८८ को राजशेखर का छोटा भाई देवनानी मुरली जब नेल्लोर से परीक्षा देकर विजयवाड़ा लौट रहा था, तो चिलकालुरिपेट के पास उसकी हत्या कर दी गयी। १९८७ में विजयवाड़ा के सूर्यरावपेट में रंगाराव के निकट सहयोगी शोभनाद्रि की हत्या उनके घर के सामने हुई थी। मुरली इस हत्या का मुख्य अभियुक्त था।

मुरली की हत्या के बाद रंगाराव और राजशेखर के गुटों के बीच लड़ाई और तेज हो गयी। रंगाराव गुट के लोगों ने अपने विरोधियों के बदले की कार्रवाई से बचने के लिए अपने बचाव की व्यवस्था की। जब मुरली की हत्या हुई थी; तब मोहन रंगाराव दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे। लेकिन उन्हें भी हत्या का एक अभियुक्त बनाया गया और जमानत नहीं मिल पायी। लेकिन लोगों के विरोध, जो 'कप्पूनाडु' के आयोजन के बाद व्यापक रूप में सामने आया, के बाद दोनों गुटों का झगड़ा बहुत बढ़ गया, फलतः विजयवाड़ा शहर और उसके आसपास के इलाकों में काफी तनाव पैदा हो गया था। ऐसे में रंगाराव ने सुरक्षा की मांग की थी और केंद्र से इसका बंदोबस्त करने को कहा था। उनकी अर्जी राज्य सरकार के पास भेज दी गयी, जिसने उन्हें दो अंगरक्षक प्रदान किये थे।

विश्वामित्र की कठिनाई : हत्या के बाद इन दोनों अंगरक्षकों का निलंबन, न्यायिक जांच का आदेश देना रंगाराव के प्रतिद्वंद्वी देवीनेनी राजशेखर 'नेहरू' का समर्पण तथा आंध्र के गृह मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक का इस्तीफा देना सामान्य बातें थीं। इससे भी महत्वपूर्ण वे कदम हैं जो रामाराव को अपने राज्य के उत्तेजित लोगों की भावनाओं को शांत करने और अपनी राजनीतिक छवि को बहाल करने के लिए उठाने पड़ेंगे। यह काम आसान नहीं होगा। हो सकता है कि अभी रामाराव राजीव गांधी की ओर से कोई कदम उठाये जाने के इंतजार में हों। ऐसा न होने पर रामाराव को विश्वामित्र की भूमिका निभाने के लिए और समय देना पड़ेगा। पहले उन्होंने फिल्मों में राम के अभिनय का फायदा उठाया था। इस बार उन्हें उनके (राम के) गुरु (विश्वामित्र) से कुछ राजनीतिक दक्षिणा लेनी होगी।

—सैयद मजीदुल हसन

मुफ़्त उपहार! 30/- रुपये मुल्य का बैग

पॉवर फ्लेक्स के साथ

भारत में पहली बार!

बुलवर्कर® का, शक्तिशाली बनानेवाला नया व्यायाम-साधन.

यह मांसपेशियों में ऐसी ताकत भर देगा-जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और माप भी सकते है. अपने घर में एकांत में **पावर फ्लैक्स** का इस्तेमाल कीजिए. यह वजन में हल्का और लाने-ले जाने में आसान है मजे-मजे में इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने शरीर को शक्तिशाली भी बनाए. वह भी बिना वजन उठाए, बिना किसी तनाव के या बिना पसीना बहाए. **पावर फ्लैक्स** आपकी शरीर की हर मांसपेशी–भुजाओं, छाती, कंधे, पीठ और पैर आदि को ताकत से भर देता है. वह भी रोज़ाना सिर्फ चंद मिनटों की कसरत से. नया **पावर फ्लैक्स**– मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के आसान और असरदार व्यायाम-साधन की कमी को पूरा करता है. यह सभी के लिए, उपयोगी है.

संपूर्ण सचित्र कोर्स–पावर फ्लैक्स के साथ.

तेज़ीसे आपके शरीरको सुगठित बनाइए.

रोज़ाना सिर्फ चंद मिनटों की कसरतसे मासपेशियों को शक्तिशाली बनाईये!

कंधे, पेट, बाहु, पैर, 'V' आकार का शरीर

नतीजे की गारंटी वर्ना आपका पैसा वापस! अगर आप इसके नतीजों से सौ फीसदी संतुष्ट न हो तो १४ दिन की बिना जोखिमवाली और मुफ्त आजमाइश की अवधि में इसे लौटा दीजिए. हम आपका पैसा वापस कर देंगे. (डाक और प्रेषण खर्च घटाकर). हम आप से इसकी वजह भी नहीं पूछेंगे.

बुलवर्कर, प्रा. लि. 15 मैथ्यू रोड, बंबई-400 004.

खेल की प्रमुख दुकानोंपर भी उपलब्ध।

यह कूपन आज ही भेजिए.

बुलवर्कर, प्रा. लि. 15 मैथ्यू रोड, बंबई- 400 004.

कृपया मुझे १४ दिनों की मुफ़्त आजमाइश के लिए नया पावर फ्लेक्स तुरंत भेज दीजिए. अगर मै इससे पूर्णतया संतुष्ट न हुआ तो आज़माइशी अवधि के भीतर पैसा (डाक व प्रेषण खर्च छोड़कर) वापस पाने के लिए सारी सामग्री लौटा दूंगा. PF-12 HIN

कृपया उचित खाने में ☑ निशान लगायें.

☐ रजि. पोस्ट पार्सल से भेजें मै 160 रुपयों का ड्राफ्ट/भा. पोस्टल ऑर्डर/मनी ऑर्डर नं. .... तारीख .... भेज रहा हू. (देय बुलवर्कर प्रा. लि. के नाम) MY-67

☐ वी.पी.पी. से भेजें. मै डाकिए को डिलीवरी मिलने पर 160 रु. अदा करने का वचन देता हू.

नाम: ....

पता ....

....

पिन: .... हस्ताक्षर ....

ABHA

अर्जुन की मांद पर धावा

जब किसी शेर को कोई उसी की मांद में चुनौती दे, तो शेर का चौंकना स्वाभाविक है। मध्यंप्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों ऐसा ही वाकया घटित हुआ। हुआ यह कि केंद्रीय मंत्रियों की जोड़ी-माधवराव सिंधिया एवं मोतीलाल वोरा ने सीधे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के गृहनगर सीधी पर धावा बोल दिया। अर्जुन सिंह, जो सिंधिया-वोरा की छापामार शैली में हो रहे दौरे रुकवाने के लिए काफी दिनों से रात दिन एक किये हुए हैं, को गुमान भी न था कि जुगल-जोड़ी विंध्य पहुंचकर ऐन सीधी पर धावा बोल देगी और लोग उनका पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। बहरहाल, दोनों नेताओं ने १३ दिसंबर को सीधी में किसान सम्मेलन में भाग लिया, नैश-विश्राम कर लोगों से मेल-मुलाकात की और अगले दिन मंझौली में हजारों की सभा को संबोधित किया। मंझौली आने का न्यौता उन्हें गोपदबनास के विधायक कमलेश्वर द्विवेदी ने दिया था। कमलेश्वर द्विवेदी पहली मर्तबा १९८० में कांग्रेस-इ के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गये थे। काफी दिनों तक उनकी गिनती कुंवर साहब के खेम में होती रही, किंतु आज की तारीख में कमलेश्वर पूरी तौर पर वोरा और सिंधिया के साथ हैं। पिछले दिनों, बताते हैं कि कुंवर साहब ने अपने एक अजीज निज सहायक के जरिये उन्हें प्रलोभन भी दिये, किंतु ये प्रलोभन अर्जुन-खेमे के रंग-ढंग से ऊबे कमलेश्वर द्विवेदी को डिगाने में विफल रहे। द्विवेदी की भांति विंध्य के गरुड़ मिश्रा, हर्ष सिंह जैसे अनेक विधायकों ने भी इन दिनों अपनी निष्ठा की डोर वोरा-सिंधिया से जोड़ रखी है। सीधी के कार्यक्रमों की एक और खास बात यह रही कि इनमें रीवा राजघराने के युवराज पुष्पराज सिंह भी खासे सक्रिय रहे। बताते हैं कि ये सारी खबरें जब अर्जुन सिंह के भोपाल में केरवां स्थित आलीशान बंगले 'देवश्री' में पहुचीं, तो विंध्य की इस ताजा हलचल को गंभीरता से लिया गया। सिंह-शिविर में फिलहाल इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि रेल-पांत से वंचित रीवा-सीधी में केंद्रीय रेल राज्यमंत्री जो राजनीतिक पटरियां बिछा गये हैं, उसे उखाड़ने के लिए किस तकनीक और हुनर का सहारा लिया जाये?

लड़ाऊ पत्रकारिता

अखबारों और राजनीति की दुनिया का रिश्ता दिनोदिन घना होता जा रहा है। इसका आभास इससे मिलता है कि मध्यप्रदेश में सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई नेताओं से दो कदम आगे बढ़कर कुछ अखबार और अखबारनवीस लड़ रहे हैं। गत्ते की तलवारें लिये शिरस्त्राण बांधे ये ऐसे जूझ रहे हैं कि पूछिये मत। हाल ही भोपाल से एक पत्रिका अर्जुन सिंह का अंध-विरोध करने की एकसूत्री नीयत से शुरू हुई लगती है। यही हाल कमोबेश एक सांध्य दैनिक का है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कई पत्र प्रदेश में ऐसे निकल रहे हैं जो मध्ययुगीन भाट या चारण-परंपरा की याद दिलाते हैं। लाभ की प्रत्याशा में प्रतिष्ठित पत्र भी पीछे नहीं हैं। प्रदेश के दो नामी-गिरामी दैनिकों ने भी इन दिनों मुख्यमंत्री का दामन थाम रखा है। खबरों के अनुसार उनके मालिक राज्यसभा में जाने की तमन्ना रखते हैं। किस्सा-कोताह यह कि ब्याज-निंदा और ब्याज-स्तुति दोनों का दौर जारी है। एक अंग्रेजी नियतकालिक ने गत दिनों ब्याज-निंदा की रौ में केंद्रीय रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया को साफ-साफ सांप्रदायिक की संज्ञा दें डाली और लिखा कि सिंधिया 'डाउनराइट कम्यूनल' हैं और उनका एकमात्र ध्येय अर्जुन सिंह को कमजोर करना है। इस पत्रिका पर यकीन करें, तो महू और ग्वालियर में सांप्रदायिक अशांति भड़काने का आरोप सिंधिया पर है। जाहिर है कि यह खबर दोनों खेमों के समझदार लोगों को नागवार गुजरी। मप्र खनिज विकास निगम के नये नवेले चेयरमैन विलास लाड 'माया' के दफ्तर में आये और कहने लगे कि यह महाराज को बदनाम करने की गंदी चाल है। बकौल लाड, "सिंधिया घराना शुरू से ही सांप्रदायिक सद्भाव में यकीन रखता आया है। ढोली बुवा और मुस्लिम फकीर मंसूर अली खां इस घराने के गुरु हैं और राजघराने के देवल में आज भी हिंदू देवी-देवताओं और मंसूर अली खां की एक साथ पूजा-अर्चना होती है। सिंधिया परंपरानुसार हर साल उर्स भी मनाते हैं। ताजियों की परंपरा वहां पुरखों के जमाने से चली आ रही है।" कहा जा सकता है कि बाहर घमासान हो या नहीं, लेकिन कुछेक अखबारनवीस महारथियों में घमासान कराने और बेवजह छवि कलंकित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

जूदेव का हिंदू बनाओ अभियान

जशपुर राजघराने के दिलीप सिंह जूदेव इन दिनों फिर से सक्रिय हैं। लगता है कि जूदेव चुप बैठने में यकीन नही रखते। कुछ दिनों पहले वे देश की सबसे गरम नगरी चांपा गये, तो वहा उन्हें देखने-सुनने खूब भीड़ जुटी। अचानक बिजली गुल होने से माइक फेल हो गया, तो भीड़ ने अपना गुस्सा मप्र विद्युत मंडल पर उतारा। जूदेव लगे हाथों राजनांदगांव भी हो आये। खबर है कि वे वहां खैरागढ़ रियासत के शिवेंद्र बहादुर सिंह (सांसद) के खिलाफ अगले लोकसभा चुनाव में अपनी चुनावी संभावनाओं का जायजा लेने गये थे। इन्हीं दिनों उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ का नारा भी बुलंद कर डाला। मगर सुर्खियों में वे तब आये, जब बिहार-मप्र की सीमा पर अवस्थित सरगुजा में सामूहिक धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण बरसों से लोगों के हिंदू से ईसाई बनने का पर्याय है, किंतु इस बार करीब पांच हजार लोग ईसाई धर्म त्याग कर फिर से हिंदू बन गये। इस उलट-धर्मांतरण के अगुवा रहे दिलीप सिंह जूदेव, जिन्होंने कसम खा रखी है कि वे इस पूरे अंचल में ईसाई मिशनरियों का मुकाबला करेंगे। 'माया' सूत्रों के अनुसार जूदेव उलट-धर्मांतरण की प्रक्रिया को आगे और गति व विस्तार देना चाहते हैं। उन्होंने 'माया' से कहा, "मैं धर्मांतरण की धारा को उलटे मोड़ना चाहता हूं। मैं अपने जीतेजी ईसाई मिशनरियों को बलात धर्म-परिवर्तन का खेल नहीं खेलने दूंगा।" जूदेव के संकल्प और उनकी सफलता से जहां रांची और जशपुर अंचल के मिशनरियों में खलबली मची हुई है, वहीं हिंदू पुनरुत्थानवादियों के दिल बल्लियों उछल रहे हैं।

—सुधीर सक्सेना

शिक्षा-माफिया को परोक्ष समर्थन : नागेंद्र झा

बिहार का शिक्षा-माफिया

शिक्षा-माफिया के बादशाह : रामलखन सिंह यादव

बिहार के धनबाद-माफिया और सहकारिता-माफिया की कथा जगत-विदित है, पर इन दोनों माफियों से ताकतवर है बिहार का शिक्षा-माफिया। आखिर यह शिक्षा-माफिया है कौन? क्या बिहार से शिक्षा-माफिया की जड़ों को उखाड़ना संभव है? 'माया' की व्यापक छानबीन :

शिक्षा-माफिया के सवाल पर बिहार में इन दिनों गजब की गहमागहमी है। धनबाद माफिया के कई धांसू शूरमा अभी जेल में कैद हैं, तो बिहार के कई सहकारिता कुबेर जेल की चौखट पर सलाखों के भीतर जाने के लिए खड़े हैं। लिहाजा, शिक्षा-माफिया को भी सीखचों में सीलबंद करने की संभावनाओं का लोग विशेषकर तब से इंतजार कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने शिक्षा-माफिया पर टूट पड़ने की मुनादी कर दी है।

तालीम की तिजारत : यों बिहार में माफिया की असंख्य प्रजातियां हैं। पर यह शिक्षा-माफिया क्या है, जो तालीम की तिजारत से बिहार की पीढ़ी-दर-पीढ़ी को बर्बाद करता आ रहा है? अगर तटस्थ होकर देखा जाये, तो धनबाद व सहकारिता माफिया का अपराध शिक्षा-माफिया की तुलना में अति नगण्य है, क्योंकि धनबाद व सहकारिता-माफिया ने तो दादागिरी के बल पर अंधाधुंध पैसा लूटकर बिहार की अर्थव्यवस्था को ही खोखला किया है, पर शिक्षा-माफिया ने तो अर्थ-संग्रह के लिए बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को खोखला कर के नयी पीढ़ी की चेतना को सिर्फ आहत ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से विक्षिप्त कर दिया है। अभी, जबकि शिक्षा-माफिया को लेकर बहस तेज है, सहज ही बिहार की यादव राजनीति के कांग्रेसी पोप रामलखन सिंह यादव से लेकर विधायक आरपी शर्मा, राजो सिंह, रामावतार वात्स्यायन सहित पूर्व शिक्षा मंत्री लोकेश नाथ झा, वर्तमान शिक्षामंत्री नागेंद्र झा के नाम तो आ ही रहे हैं, साथ ही बिहार राजनीति के कई पहुंचे हुए उन अलंबरदारों द्वारा शिक्षा के नाम पर किये गये गोरखधंधों का सवाल भी खड़ा हो रहा है जो अर्से से अपने-अपने नाम पर अनगिनत कालेज-स्कूल खोलकर दुकानदारी चला रहे हैं।

शिक्षा-व्यवसाय के महंत : आरपी शर्मा

"जो लोग अपने जीवनकाल में ही अपने नाम पर कालेज-स्कूल खोलते हैं, वे अपना जीवित श्राद्ध ही करते हैं। पर बिहार में विगत एक दशक से अधिकांश राजनीतिज्ञ यही काम कर रहे हैं। दरअसल, इन भ्रष्ट राजनेताओं को यह भरोसा ही नहीं कि उनके निधन के बाद लोग श्रद्धावश उनकी याद में कोई कालेज अथवा स्कूल खुलवाने में आस्था रखेंगे।" कहते हैं, 'माया' से एक पूर्व कुलपति। शिक्षा-माफिया की दुनिया के उत्तराधिकारी भी अभी से इस व्यवसाय की बागडोर पूरे दमखम से थामने की तैयारी में जुटे हैं। रामलखन सिंह यादव के सांसद पुत्र प्रकाश चंद्र जहां अपने पिता के संरक्षण में पूरे बिहार में चलाये जा रहे तकरीबन ६० कालेजों व स्कूलों के शिक्षकों को आये दिन अपनी गुंडावाहिनी के धमंकावे में रखते हैं, वहीं बिहार के शिक्षामंत्री नागेंद्र झा के विधायक पुत्र मदनमोहन झा भी दरभंगा में अपने पिता के नाम पर खुले 'नागेंद्र झा महिला कालेज' की व्यवस्था के सूत्रधार हैं।

मदनमोहन झा द्वारा 'बिहार अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद्' में किये गये लगभग छह-सात लाख के एक गोरखधंधे ने सबको चौंका कर रख दिया। मदनमोहन झा ने अपनी अध्यक्षता में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी एंड मैनेजमेंट' नामक एक संस्थान खोल डाला और लाखों की कमायी की। बिहार अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् में सचिव के पद पर शिक्षामंत्री ने

मैथिली विश्वविद्यापीठ
MAITHILI UNIVERSITY
मैथिली विश्वविद्यालय

शिक्षा का मजाक : फर्जी मैथिली विश्वविद्यालय

दरभंगा में दिनराज शांडिल्य नामक धूर्त ने डंके की चोट पर अरसे तक फर्जी 'मैथिली विश्वविद्यालय' चलाया और दक्षिण भारत के छात्रों को बाकायदा डिग्री देता रहा। दरअसल, दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय भी है, सो दिनराज शांडिल्य के फर्जी मैथिली विश्वविद्यालय से बहुतों को भ्रम हो जाता था। दक्षिण भारत में इस जाली विश्वविद्यालय से 'करेसपोंडेंस कोर्स' कर प्राप्त डिग्री के आधार पर कई लोग नौकरी भी कर रहे हैं।

रूपनारायण झा को तैनात कर ही रखा था। लिहाजा, भक्तिभाव में रूपनारायण ने मदनमोहन झा के इस नवोदित इंस्टीट्यूट को परिषद् का लगभग सात लाख का डाटा-प्रोसेसिंग का कार्य तमाम नियमों को ताक पर रख दे दिया। एक प्राइवेट संस्थान को इतना बड़ा काम दिया जाना किसी से छिपा नहीं रह सका, क्योंकि शिक्षामंत्री के पुत्र के इस इंस्टीट्यूट के पास 'डाटा प्रोसेसिंग' के पर्याप्त साधन ही नहीं थे। लिहाजा, पटना के फ्रेजर रोड स्थित 'मौर्या डाटा प्रोसेसर एंड कंसलटेंट' को यह काम शिक्षामंत्री के पुत्र ने चुपचाप करने के लिए दे दिया। दरअसल, १९८९ में होनेवाली इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे तकरीबन साढ़े तीन लाख विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड की तैयारी के लिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षामंत्री के पुत्र के उस लचर प्राइवेट संस्थान को दी गयी थी जिसके पास अपना कोई साधारण नेटवर्क तक नहीं था। जानकारों का कहना है कि अंतरविश्वविद्यालय शिक्षा परिषद् में शिक्षामंत्री ने सैकड़ों की संख्या में बहालियां भी करायीं। मदनमोहन झा की भांति केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही के पुत्र हेमंत शाही भी अपने पिता के नाम पर खुले कालेजों में खास दखल रखते हैं। हालांकि हेमंत की रुचि ज्यादा परिवहन व्यवसाय में है।

शिक्षा के घुन : "बिहार के मैथिल मंत्रियों ने बिहार की शिक्षा को रोगग्रस्त कर दिया। शिक्षा माफिया की जड़ों को ये ही सींचते रहे हैं।" कहते हैं बिहार के एक वयोवृद्ध दिग्गज शिक्षाविद्। बात भी सही है, क्योंकि पिछले दिनों लगभग प्रत्येक मंत्रिमंडल में, चाहे वह स्व० चंद्रशेखर सिंह की सरकार रही हो या बिंदेश्वरी दुबे की या फिर अभी भागवत झा आजाद की सरकार हो, शिक्षामंत्री या तो नागेंद्र झा होते रहे हैं या फिर लोकेश नाथ झा। दोनों मैथिल ब्राह्मण हैं। स्व० चंद्रशेखर सिंह के पूर्व स्वयं मिथिलापति डा० जगन्नाथ मिश्र ही मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनके काबीना में करमचंद भगत सरीखे आदिवासी नेता डमी के रूप में शिक्षामंत्री रहते थे और शिक्षा के क्षेत्र में सारे जोड़-तोड़ और घालमेल स्वयं डा० जगन्नाथ मिश्र ही किया करते थे। डा० जगन्नाथ मिश्र ने भी अपने नाम पर संस्थाएं खुलवायीं और राजो सिंह तथा रघुनाथ झा सरीखे उनके मंत्रिमंडल के चर्चित राज्यमंत्रियों ने भी ताबड़तोड़ अपने-अपने नाम पर स्कूल-कालेज खुलवा डाले। रघुनाथ झा (जो बिहार विधान सभा में जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं) ने तो अपने नाम पर सीतामढ़ी में बस एक ही कालेज खुलवा कर संतोष कर लिया, पर राजो सिंह ने तो कमाल कर दिया। राजो ने अपने नाम पर तो कालेज व स्कूल खुलवाये ही, साथ ही रघुनाथ झा और तत्कालीन बिहार विधानसभाध्यक्ष राधानंदन झा के नाम पर भी अपने क्षेत्र में स्कूल व कालेज खोल डाले। मसलन, ओठमा में राजो सिंह कालेज व स्कूल खुला, भदौंस, करंडे, अमारी, शोभानपुर, नौआगढ़ी, पिंजरी, और आदि स्थानों में राजो सिंह हाई स्कूल तथा इसके अलावा सिकंदरा के निकट मंजोस में 'रघुनाथ झा, राजो सिंह हाई स्कूल' खुला और शेखपुरा के पास 'राधानंदन झा हाई स्कूल' की भी स्थापना राजो सिंह ने की। राजो सिंह अभी शेखपुरा से निर्दलीय विधायक हैं। पर ऐसा नहीं कि बेचारे राजो सिंह ही स्कूल-कालेज खोलकर अपने चहेतों की भरती व इन संस्थानों से धन-संग्रह कर राजनीति कर रहे हों। अगर इसका जायजा लिया जाये तो इसकी फेहरिस्त में एक से एक महारथी के नाम आयेंगे। डा० जगन्नाथ मिश्र के नाम पर 'जगन्नाथ मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेक्नालॉजी' के अलावा अनेक संस्थाएं हैं, जो लोगों को उपकृत करने व धन-संकलन की स्रोत रही हैं। पटना स्थित 'एल-एन मिश्रा इंस्टीट्यूट' डा० जगन्नाथ मिश्र की विक्षुब्ध राजनीति का सचिवालय ही कहा जाता था जिसे बिंदेश्वरी दुबे ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सरकारी कब्जे में ले लिया। पूर्व विदेश मंत्री बलिराम भगत के नाम पर बिहार में कई कालेज व स्कूल चल रहे हैं और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इन स्कूल-कालेजों का मकसद शिक्षा के प्रसार से ज्यादा अपने समर्थकों की बहाली व धन उगाही रही।

बिहार की वर्तमान राजस्वमंत्री उमा पांडेय भी भला इस दौर में कैसे पीछे रहतीं? सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा के नाम पर भला शैक्षणिक संस्थाओं का पुंज बिहार में हो तो क्या आश्चर्य? हां, इतना जरूर है कि सत्येंद्र नारायण ने और राजनीतिज्ञों की भांति अपने नाम पर चल रही शैक्षणिक संस्थाओं को धन-संकलन का साधन नहीं बनाया। बिहार में ऐसे विधायकों की कमी नहीं जिन्होंने विधायक के तौर पर क्षेत्रीय विकास के मद में मिलनेवाली राशि से जोर-जबर्दस्ती कर अपने नाम पर चल रहे कालेजों का भवन तैयार कराया हो। उन्होंने उन कालेजों में अपने लठैतों की बहाली की। थर्ड क्लास एमए पास लोगों को भी व्याख्याता बना दिया, बस हो गयी पूरे क्षेत्र में जय-जयकार। चुनावी-दंगल में कालेज की पूरी सेना उनके लिए जान गंवाने को तैयार रहती है।

अस्थावां से निर्दलीय विधायक आरपी शर्मा की कहानी दिलचस्प है। आरपी शर्मा पटना स्थित टीपीएस कालेज में आज भी दर्शन शास्त्र के व्याख्याता की नौकरी में हैं। पर राजधानी पटना के शैक्षणिक व्यवसाय के प्रमुख महंतों में उनकी गिनती होती है। आरपी शर्मा जबतक टीपीएस कालेज की प्राध्यापकी में सक्रिय रहे, तबतक उनकी अपने प्राचार्य कुटेश्वर प्रसाद सिंह से कभी नहीं बनी। लिहाजा, आरपी शर्मा ने ठान लिया कि पूरे पटना में वे अपने नाम की शैक्षणिक संस्थाओं का जाल बिछा कर रहेंगे। आरपी शर्मा ने आरपीएस कालेज, आरपीएस महिला कालेज, आरपीएस रेजीडेंशियल स्कूल आदि अनगिनत स्कूल-कालेजों की बाढ़ लगा दी। पटना के नयाटोला में आरपीएस कालेज की स्थापना १९७९ में की गयी। आरपी शर्मा ने कालेज सचिव के रूप में अपने बड़े भाई के साले भवानी प्रसाद सिंह का नाम दिखावे के लिए रखा। पर परदे के पीछे से सर्वेसर्वा वही रहे। आरपीएस कालेज के प्राचार्य ने ही एक बार आरपी शर्मा के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा दिया, पर जोड़-तोड़ में माहिर शर्मा ने फिर प्राचार्य को पटा लिया। आरपी शर्मा शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवसाय में आर्थिक रूप से जब काफी समृद्ध हो गये, तो उनकी तबीयत विधायक बनने की हो आयी। लिहाजा, पिछले विधानसभाई चुनाव में वे थैली लेकर कांग्रेस के

ADMISSION NOTICE FOR M.B.B.S. COURSE

Applications are invited from eligible candidates for admission to Ist M.B.B.S. course for academic year 1987-88.

Application forms and prospectus can be had from the Office on payment of Rs 45/-in cash or by crossed demand draft payable in favour of, **Katihar Medical College, Katihar Payable at Patna.**

Last date of receipt of application form in the office is **20th November. 1987.** Foreign students may also apply.

Chairman,
Al-Karim Educational
Patna.

Dr. S.M. NAWAB
FRCS, FICS, MRCOG
Principal
Ex-Principal Darbhanga Medical College
And Shrikrishna Medical College, Muzaffarpur.

एमबीबीएस में दाखिले का इश्तहार

टिकट के लिए कई राजदरबारों में भटकते रहे। पर शर्मा को दुर्भाग्यवश टिकट नहीं मिला। पैसा हो तो बिहार में विधायक बनना आसान है, सो कांग्रेस-टिकट न मिलने पर आरपी शर्मा अस्थावां से निर्दल ही लड़ गये और जीत कर विधान सभा में पहुंचे। जाहिर है, उनके शैक्षणिक व्यापारी के स्वरूप में अब राजनीति की कलगी भी लग गयी। फिर तब से आरपी शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इधर तो वे शिक्षा-व्यवसाय के साथ-साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी रोजगार करने में व्यस्त चल रहे हैं। यह रही आरपी शर्मा की कहानी।

शर्मा तो फिर भी किसी रूप में शिक्षा से जुड़े थे, पर पटना के शिक्षा-व्यवसाय के नामी सेठ रामावतार वात्स्यायन का तो शिक्षा से दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं था। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यरत रामावतार सिंह नामक एक किरानी को १९७० में नौकरी से निलंबित कर दिया गया, तो रामावतार के सामने बेरोजगारी की स्थिति आ गयी। अपने परिवार को दो जून की रोटी जुटाकर देने की स्थिति में भी रामावतार नहीं रह गये थे। पर अचानक रामावतार के दिमाग में एक अनूठा विचार कौंधा कि क्यों न शिक्षा के व्यवसाय में ही वे अपने भाग्य की आजमाइश करें। बस वे इस दिशा में पिल पड़े। किरानी होने के कारण पटना सचिवालय के शिक्षा विभाग में कार्यरत किरानियों से भी उनका अच्छा परिचय था ही, इसलिए उन्हें अपनी शिक्षण संस्थाओं का सरकारी चक्कर निबटाने में कोई परेशानी भी नहीं थी। रामावतार सिंह ने 'जेडी वीमेंस कालेज' और 'जेडी गर्ल्स हाई स्कूल' सरीखी अनगिनत शैक्षणिक संस्थाओं का देखते-देखते पटना में अंबार लगा दिया और कुछ ही वर्षों में पटना में वे शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवसाय के नये महंत के रूप में प्रसिद्ध हो गये। पटना, रांची और रामगढ़ के अतिरिक्त बिहार के कई प्रमुख शहरों में भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से उनकी शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवसाय का जाल बिछ गया और किरानी की नौकरी में अर्थाभाव से गुजर रहे रामावतार सिंह की आर्थिक हैसियत का कुछ ही वर्ष में अद्भुत ढंग से कायाकल्प हो गया। पर जब सरकार द्वारा रामावतार सिंह की दो प्रमुख संस्थाओं 'जेडी वीमेंस कालेज' और 'जेडी गर्ल्स हाई स्कूल' को ले लिया गया, तो अपनी अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को सरकार से बचाये रखने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और रातों-रात वे रामावतार सिंह से रामावतार वात्स्यायन बन बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने 'विश्व बुद्ध परिषद्' नामक संस्था की स्थापना कर अपनी सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बुद्ध परिषद् से संबद्ध कर दिया, ताकि सरकार उनकी आय के इन साधनों को अपने कब्जे में न ले सके। 'विश्व बुद्ध परिषद्' का अध्यक्ष रामावतार ने राष्ट्रपाल भिक्षुक नामक एक बौद्ध को बनाया और स्वयं सचिव बन बैठे। बौद्ध रामावतार संप्रति पटना में सिद्धार्थ महिला महाविद्यालय, सिद्धार्थ महिला शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, संत एमजी हाई स्कूल और रांची में संघमित्रा कालेज के अतिरिक्त कई संस्थाओं का संचालन करते हुए शिक्षा-जगत में अपनी चाशनी घोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों सिद्धार्थ महिला कालेज की शिक्षिकाओं ने रामावतार द्वारा किये जा रहे शोषण के विरुद्ध कई जगह फरियाद की कि रामावतार इस कालेज को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्था करार दिलवाकर उन लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करने की तैयारी में हैं। बौद्ध बन जाने के कारण रामावतार को न सिर्फ शिक्षा की दुकानदारी में फायदा हुआ, बल्कि बौद्ध धर्मावलंबी के रूप में विदेश यात्राओं का भी उनका दौर बढ़ गया।

रामावतार की तरह जमशेदपुर में भी ए रवि नाम के एक सज्जन अवतरित हुए हैं जो 'बौद्ध एजुकेशन सोसाइटी' के तहत 'गौतम बुद्ध कालेज ऑफ एजुकेशन' के नाम पर बीएड व टीचर्स ट्रेनिंग की दुकान चला रहे हैं। हाल में जमशेदपुर के नागरिक कल्याण परिषद् के महामंत्री वैदेही शरण सिंह ने स्थानीय अनुमंडलाधिकारी एजेके राव को पत्र देकर अनुरोध किया कि शहर में बौद्ध शैक्षणिक संस्था के नाम पर चल रहे इस 'फ्राड' को रोका जाये।

फर्जी मैथिली विश्वविद्यालय: कहानी यहीं खतम नहीं होती। दरभंगा में दिनराज शांडिल्य नामक एक धूर्त ने डंके की चोट पर अरसे तक फर्जी 'मैथिली विश्वविद्यालय' चलाया और दक्षिण भारत के छात्रों को बाकायंदा डिग्री देता रहा। दरअसल, दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय भी है, सो दिनराज शांडिल्य के फर्जी मैथिली विश्वविद्यालय से बहुतों को भ्रम हो जाता था। दक्षिण भारत में इस जाली विश्वविद्यालय से 'करेसपोंडेंस कोर्स' कर प्राप्त डिग्री के आधार पर कई लोग नौकरी भी कर रहे हैं। जब दरभंगा के इस जाली विश्वविद्यालय का पता सरकार को चला, तो राजभवन से नोटिस जारी की गयी कि छात्र इस जाली विश्वविद्यालय से बचें।

स्व० चंद्रशेखर सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में जब नागेंद्र झा शिक्षामंत्री थे तो प्रौढ़ शिक्षा में लालटेन की खरीद में हुए घपले से लेकर कई घपलों में उनका नाम आया और अब जबकि वे पुनः भागवत झा आजाद के राज में शिक्षामंत्री की कुरसी पर आसीन हैं, तो शिक्षा विभाग को बिहार में भ्रष्टाचार का एकमात्र पर्याय माना जा रहा है। ऊपर से नीचे तक शिक्षा विभाग में एकमात्र पैसे की ही महिमा है।

यह बात बहुत पुरानी नहीं जब बिंदेश्वरी दुबे के मंत्रिमंडल में लोकेश नाथ झा शिक्षा विभाग के काबीना मंत्री हुआ करते थे। एक दिन राजनीतिक लॉबी के तहत बिंदेश्वरी दुबे अपने गुट के विधायकों को पार्टी देना चाहते थे। उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री लोकेशनाथ को बुलाकर अपने यहां पार्टी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। लोकेश नाथ को असमंजस में देख तत्कालीन मुख्यमंत्री दुबे ने शंका का समाधान यह कहते हुए किया था कि पार्टी के लिए अगर पैसे नहीं जुट रहे हों, तो किसी कालेज को 'एफलिएशन' दे दें, पैसे जुट ही जायेंगे। कालेजों को मान्यता देने के नाम पर पैसों की उगाही करने के लिए लोकेशनाथ विख्यात थे। बिहार विधान परिषद द्वारा गठित एक विशेष समिति ने अपने जांच प्रतिवेदन में जिस तरह लोकेशनाथ झा को आड़े हाथों लिया था, वह बिहार में शिक्षा-माफिया के एक कुत्सित स्वरूप को ही उजागर करता था। विधान परिषद् की इस विशेष समिति को राज्य के

चतुर्थ चरण में अंगीभूत नये ३६ महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों एवं गैरशिक्षक कर्मचारियों के ३० अप्रैल, १९८६ तक प्रस्तावित पदों के सृजन एवं वेतन-भुगतान और सेवा अंतर्लीनीकरण के संबंध में सरकार द्वारा २६ अगस्त, १९८६ को सदन में दिये गये आश्वासन के कार्यान्वयन में विलंब तथा इस बीच सरकार एवं विश्वविद्यालयों के विभिन्न स्तरों पर किया गया विलंब एवं अनियमितताएं और उनके लिए दोषी व्यक्तियों तथा उनसे संबंधित विषयों की जांच करना था। अपनी जांच के क्रम में विधान परिषद् की विशेष समिति ने पाया कि राज्यादेश के मुताबिक कहीं भी कार्य संपन्न नहीं किया गया था।

विधान परिषद् की विशेष समिति ने लोकेशनाथ झा को बिलकुल कठघरे में खड़ा करते हुए विस्फोटक टिप्पणी की कि ३६ महाविद्यालयों को छोड़ अन्य ऐसे दूसरे अंगीभूत महाविद्यालयों में पद सृजन के संबंध में जाने क्यों शिक्षामंत्री भयानक उदारता का रुख रखे हुए हैं और इस उदारता की पराकाष्ठा यह है कि कुछ महाविद्यालयों में बिना किसी छानबीन के, यहां तक कि शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा के उपनिदेशक तथा शिक्षा आयुक्त द्वारा पद-सृजन के प्रस्ताव को छात्रों की संख्या पर आधारहीन बतलाने पर भी पद सृजन के सभी आधारों को नजरअंदाज करते हुए अत्यधिक पद-सृजन का आदेश दे दिया। इस विशेष कृपा के तहत कालेजों में सहरसा का सर्वनारायण सिंह कालेज, पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह कालेज तथा मसौढ़ी के जतीकचक में चल रहा डीएन कालेज था। इन कालेजों में शिक्षामंत्री द्वारा बेहिसाब पद-सृजन का आदेश किसी को चौंका सकता है। सर्व नारायण सिंह कालेज, सहरसा में पहले से ४९ वित्त रहित पद सृजित थे। विश्वविद्यालय ने ८ फरवरी, १९८६ को पद-सृजन का जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें विभिन्न विषयों में कुल मिलाकर ४२ और कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन की अनुशंसा की गयी थी। निश्चित रूप से किसी-न-किसी कारण से शिक्षामंत्री लोकेश नाथ झा की कृपा से आश्वस्त होकर इस कालेज ने सात माह के बाद २६ सितंबर, १९८६ को विश्वविद्यालय से पद-सृजन का एक दूसरा प्रस्ताव भिजवाया जिसमें ७२ अतिरिक्त पदों की मांग की गयी। आश्चर्य यह है कि मात्र सात माह के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या एवं शैक्षणिक कार्यभार में दोगुने का अंतर कैसे हो गया? इतने पदों के सृजन का यह प्रस्ताव निश्चित रूप से संदेहात्मक तथा कार्यभार के आधार पर औचित्य से परे बताते हुए संचिका में उपनिदेशक, उच्च शिक्षा सुंदरदेव सिंह ने पद-सृजन के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पद-सृजन के प्रस्ताव को अनुचित बताया। विधान परिषद् की विशेष समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा 'किंतु माननीय शिक्षामंत्री किसी कारणवश, जो नहीं कहने पर भी स्पष्ट ही है, महाविद्यालय के अभिलेखों की जांच नहीं करवाना चाहते थे। वे महाविद्यालय को पदों का मुहमांगा दान देना चाहते थे और इतने आतुर तथा तत्पर थे कि उन्होंने स्वीकृति का आदेश देते हुए लिखा कि पद सृजन का आधार मुख्यत: विश्वविद्यालय की अनुशंसा ही होती रही है, कोई दूसरा आधार नहीं होता। विश्वविद्यालय द्वारा पृष्ठ १२८/ १२७ पर अनुशंसित पदों का सृजन किया जाता है।'

जांच के उसी क्रम में विधान परिषद् की समिति को विश्वविद्यालयों के स्तर पर की गयी अनेक अनियमितताओं का पता लगा। प्राय: सभी विश्वविद्यालयों ने जांच प्रक्रिया में उसके लिए राज्य सरकार द्वारा विहित मापदंड की अवहेलना की थी। उचित तो यह था कि प्राचार्य और सचिव द्वारा जो सूचियां दीं गयीं थीं, उनका सत्यापन शासी निकाय की कार्यवाही, वेतन भुगतान बही, उपस्थिति पंजी आदि महत्वपूर्ण कागजातों के आधार पर जांच के बाद ही सारी सूचियों को प्रमाणित किया जाना था, पर विश्वविद्यालयों में कहीं भी इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। जांच के क्रम में जब विधान परिषद् की समिति ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से यह प्रश्न किया कि उन्होंने किस आधार को अपनाया है, तो प्राय: सभी ने उत्तर दिया कि शासी निकाय की कार्यवाही एवं नियुक्ति पत्रों को ही आधार माना गया है। पर जब परिषद् की समिति ने यह प्रश्न किया कि उन सूचियों में ऐसे भी नाम हैं जिनका वेतन भुगतान बही में नाम नहीं है और उपस्थिति पंजी में भी नाम नहीं है, तो सब निरुत्तर थे। समिति ने पाया कि सभी विश्वविद्यालयों ने ऐसे बहुत से केस अनुशंसित किये थे।

बौद्ध बन शिक्षा का धंधा: रामावतार वात्स्यायन

अनियमितताएं: भागलपुर विश्वविद्यालय में कई तरह की अनियमितताएं इस संबंध में पायी गयी। उदाहरणस्वरूप भागलपुर विश्वविद्यालय के कोआर्डिनेटर प्रो० रामेश्वर प्रसाद सिंह ने खगड़िया महिला कालेज में अपनी पत्नी शीला सिंह का नाम अवैधानिक ढंग से कालेज की सूची में डलवा दिया। विधान परिषद् की जांच समिति ने टिप्पणी की कि 'यह संदिग्ध है कि शीला सिंह की नियुक्ति कब हुई, क्योंकि उनकी नियुक्ति के कोई आधारभूत प्रमाण नहीं मिले। संभावना यही है कि विश्वविद्यालय द्वारा 'स्क्रीनिंग' के समय उनका नाम लिस्ट में डलवा दिया गया, क्योंकि वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कोआर्डिनेटर रामेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी हैं।'

विधान परिषद् की समिति ने भागलपुर विश्वविद्यालय के कालेजों में व्याख्याता पद पर हुई अनगिनत रहस्यमय नियुक्तियों पर प्रकाश तो डाला ही, साथ-साथ मगध विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय आदि में भी व्याख्याता पद पर हुई रोमांचक नियुक्तियों का सवाल उठाया। मगध विश्वविद्यालय के प्रसंग में समिति ने पटना सिटी स्थित गुरू गोविंद सिंह कालेज में प्राचीन इतिहास एवं एशियाई अध्ययन विषय में अंबुज किशोर झा की व्याख्याता पद पर नियुक्ति का सवाल उठाया था कि कैसे इस विषय में प्रथम पद पर कार्यरत नरेंद्र कुमार सिंह को चौथे पद पर ले जाकर प्रथम पद पर अंबुज को बिठा दिया गया।

सवाल-दर-सवाल: बहरहाल, दुबे राज के पतन के साथ ही लोकेशनाथ झा तो शिक्षामंत्री पद से चले गये। विधान परिषद की जांच समिति की रिपोर्ट भी आ गयी। चूंकि लोकेशनाथ झा मंत्री नही रहे, इसलिए उनके गलत फैसलों को बिसरा दिया गया, साथ ही विधान परिषद् की विशेष समिति की जांच-रपट ठंडे बस्ते में आज भी सो रही है। पर सवाल यह है कि लोकेशनाथ झा के जमाने में चोर दरवाजों से कालेजों में व्याख्याता के रूप में घुसे लोग तो कालेजों में व्याख्याता के रूप में बरकरार रह ही गये। ऐसे व्याख्याता अपने छात्रों को किस गर्त में पहुंचा कर छोड़ेंगे, इसकी कल्पना ही रोंगटे खड़ी करनेवाली है। अपनी नौकरी के २५-३० वर्षों में ऐसे व्याख्याताओं से हजारो-हजार लड़के कैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे? इसलिए शिक्षा विभाग से लेकर कालेज-स्कूल की कक्षाओं तक शिक्षा-माफिया की जड़ों तक पहुंचना होगा। मुख्यमंत्री आजाद ने अगर यह दावा किया है कि वे बिहार से शिक्षा-माफिया को उखाड़ फेकेंगे, तो उन्हें पहले से चोर दरवाजों से नियुक्त रद्दी व्याख्याताओं की भी बर्खास्तगी करनी होगी और साथ ही पहले की गयी विभिन्न जांच समितियों की रपट पर कार्रवाई करनी होगी। बेशक धनबाद माफिया और सहकारिता माफिया से ज्यादा जटिल शिक्षा-माफिया से टकराना है, क्योंकि अधकचरी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों को छोड़ना सूर्यदेव सिंह और तपेश्वर सिंह को छोड़ने से ज्यादा खतरनाक है।

पर क्या रामलखन सिंह यादव जैसे शिक्षा-माफिया पर आजाद कार्रवाई करेंगे? अगर यह

आकलन किया जाये कि शिक्षा के बाजार का धन्नासेठ कौन है, तो छूटते हुए लोग कहेंगे—रामलखन सिंह यादव। अय्यर कमीशन के चक्कर में फंसने के बाद से कभी रामलखन सिंह यादव दोबारा मंत्री नहीं हो सके। रामलखन सिंह यादव अब वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए अब शैक्षणिक व्यवसाय की अपनी कीमती गद्दी पर उन्होंने अपने सांसद पुत्र प्रकाश चंद्र का राज्याभिषेक कर दिया है। कुछ माह पूर्व जब पटना के अनीसाबाद में चल रहे 'रामलखन सिंह यादव कालेज' के शिक्षकों ने अपने जायज़ हकों की मांग की, तो न सिर्फ प्रकाशचंद्र ने निरीह शिक्षकों को अपने गुंडों से ठुकवाया, बल्कि एक व्याख्याता गुलाम गौस का अपहरण भी करवा लिया गया। जाहिर है, इन कालेजों की व्यवस्था पूरी-की-पूरी माफिया शैली में चलती है।

अनूठी धंधेबाजी: बिहार में शिक्षा की धंधेबाजी अनूठी है। बिहार सरकार वित्तीय बदहाली के नाम पर कालेजों को वित्तरहित मान्यता प्रदान करती है। शिक्षा माफियों के लिए इतना ही काफी है। बिहार में फिलहाल तक़रीबन ढाई सौ वित्तरहित मान्यता प्राप्त कालेज चल रहे हैं। 'सबके दाता राम' वाले भाव में शिक्षा-माफिया जगत के खिलाड़ी डोनेशन के नाम पर शिक्षकों व छात्रों से अच्छी खासी वसूली करते रहते हैं। जमीन पर कब्जा जमाने के लिए भी शिक्षा-माफिया कालेज खोला करते हैं। मसलन, मुंगेर के एक विधायक ने कई एकड़ के कीमती सरकारी भूखंड पर अपने नाम से कालेज खोल कर कब्जा कर लिया।

'डोनेशन' की महिमा बीएड के नामांकन में भव्य रूप से दिखायी देती है। किसी स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति को स्कूल में शिक्षक की नौकरी पाने के लिए बीएड की डिग्री आवश्यक है। लिहाजा, इसकी डिग्री सुलभ कराने के लिए अनगिनत शिक्षण संस्थाएं प्रदेश में चल रही हैं। बस इस हाथ से डोनेशन दीजिए और उस हाथ से डिग्री लीजिए। एक तरफ जहां बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय 'ओवर ड्राफ्ट' की स्थिति से गुजर रहे हैं और सरकार पर विश्वविद्यालयों के तकरीबन डेढ़ अरब रुपए बाकी हैं, वहीं शिक्षा-माफिया बिना पूंजी के अरबों का मुनाफा कमा रहे हैं। जहां बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना दुर्लभ है, वहीं शिक्षा-माफिया अपने कालेजों में नियुक्त शिक्षकों से ही वेतन लेते हैं। हाल में काफी हाय-तौबा मचाने के बाद बिहार सरकार ने शिक्षकों व विश्वविद्यालयीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किसी तरह ६.९० करोड़ रुपए दिये। पर हर महीने अगर वेतन की यही स्थिति रही, तो पता नहीं पुराने प्रतिष्ठित कालेजों के शिक्षकों की क्या दशा होगी? पर आर्थिक तंगी तो सीधे-सच्चे शिक्षकों के भाग्य में है, शिक्षा-माफिया तो प्रतिदिन के हिसाब से समृद्ध ही हो रहे हैं।

शिक्षा-माफिया सिर्फ कालेज-स्कूल खोल धंधा करने के चक्कर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड, बिहार अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बिहार कालेज सेवा आयोग, मदरसा बोर्ड, संस्कृत शिक्षा बोर्ड से लेकर प्रदेश की विभिन्न भाषाई अकादमियों तक में हाथ-पांव फैलाये हुए हैं। पाठ्य पुस्तकों की जाली छपाई में भी शिक्षा-माफिया का वर्चस्व है। पाठ्य-पुस्तक निगम से सांठ-गांठ कर जाली पुस्तकों की छपाई का मुनाफेदार कारोबार प्रदेश में जमकर फलफूल रहा है। जिस सूबे का बच्चा जाली पाठ्य पुस्तक पढ़ने को विवश है, उस प्रदेश की चेतना किस घाट लगेगी, उसका अनुमान भी लगाने की शायद जरूरत नहीं। बिहार में स्कूलों की स्थिति का ही जायजा लिया जाये, तो पता चलेगा कि शिक्षा की जड़ें ही इस सूबे में बिना मिट्टी की हैं।

अपने नाम पर संस्थाएं: राजो सिंह

छतहीन स्कूल: बिहार में अधिकांश सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल या तो बगैर भवन के हैं या जो उनके पास भवन हैं भी, उन्हें खतरनाक खंडहर कहना ज्यादा उत्तम होगा। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड मुख्यालय में स्थित एक प्राथमिक स्कूल मात्र डेढ़ कमरे में चलता है। यह डेढ़ कमरा भी उस स्कूल के प्राचार्य ने लोगों से भिक्षाटन कर बनवाया। कुछ माह पूर्व आये भूकंप में ये डेढ़ कमरे बुरी तरह दरक गये और हर पल गिरने को तैयार हैं, पर बच्चे पढ़ने कहां जायें? मुमकिन है कि किसी दिन खबर मिलें कि सैकड़ों बच्चे उस कमरे में दब कर मर गये। देश के श्रम मंत्री बिंदेश्वरी दुबे के गांव महुआंव और उसके अगल-बगल स्थित गांव बगैर भवन के हैं। पंचम राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के मुताबिक बिहार में अभी लगभग दस-बारह हजार विद्यालय बगैर भवन के हैं। यों केंद्र सरकार ने विद्यालयों के भवन बनाने के लिए १८ करोड़ की राशि कुछ समय पूर्व दी थी, पर वह राशि किस शिक्षा माफिया की जेब में गयी, इसका पता अब तक नहीं चला है।

यह तो रही स्कूलों के भवन की बात। कई हाई स्कूल तो ऐसे हैं जो बस एक ही शिक्षक के दम पर चलते हैं। गोपालगंज जिले के हथुआ स्थित हाई स्कूल में सरकार ने मात्र एक शिक्षक पद की स्वीकृति दे रखी है। वे महोदय अकेले ही सारी कक्षाएं ले लेते हैं। मुफ़स्सिल के स्कूलों में ऐसे भी शिक्षक हैं जो स्वेच्छा से खेती आदि के समय स्कूल में अवकाश घोषित कर गांव में खेती-बारी भी कर लेते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अधकचरे ढंग से पढ़े-लिखे लोगों के करिश्मों से प्रभावित होकर कई अनपढ़ अपराधियों का भी उत्साह बिहार की शिक्षा में कुछ कर गुजरने के लिए जगा है। कुछ समय पूर्व बेगूसराय में ऐसे ही चंद अनपढ़ों ने बाकायदे विश्वविद्यालय बनाकर नियुक्तियां कीं और पैसे लिये। इस विश्वविद्यालय के प्रधान आरआर मिश्र ही मात्र मैट्रिक तक पढ़े थे, शेष उनके विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अंगूठा-छाप थे। यह फर्जी विश्वविद्यालय पुलिस की पकड़ में आ गया, तो आरआर मिश्र सहित उनके सभी पदाधिकारी जेल चले गये। पर बिहार में ऐसे लोगों की भरमार है जो चुटकियों में विश्वविद्यालय कायम कर स्वयंभू कुलपति बन कितनों को चूना लगाने में कामयाब होते हैं।

कई वर्ष पूर्व प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलकर डोनेशन से डाक्टर बनानेवाले शिक्षा माफिया की एक कारगर जमात पूरे प्रदेश में जोर-शोर से आयी थी। पर बाद में सभी मेडिकल कालेजों को सरकार द्वारा ले लिये जाने के बाद यह सरकारी घोषणा हुई कि अब इस तरह के प्राइवेट मेडिकल कालेज न खोले जायें। पर पटना में 'कटिहार मेडिकल कालेज' नामक एक संस्था डंके की चोट पर स्थानीय दैनिकों में एमबीबीएस में नामांकन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करती रहती है। आश्चर्य यह भी है कि कटिहार मेडिकल कालेज पटना में चल रहा है। 'अल करीम ट्रस्ट' नामक संस्था द्वारा संचालित इस विचित्र मेडिकल कालेज पर कई माह पूर्व सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की, पर इसके बावजूद 'कटिहार मेडिकल कालेज' का कथित कारोबार जोर-शोर से चल रहा है। अल करीम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इंका विधायक मुबारक हुसैन बताये जाते हैं।

क्या सचमुच बिहार से शिक्षा-माफिया की जड़ें उखड़ पायेंगी? पटना विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ शिक्षक कहते हैं, "इसकी उम्मीद कम दीखती है। कई विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षक भी माफिया से कम नहीं। एक विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक ने एमए की परीक्षा में अपनी बेटी के लिए परीक्षा हॉल में घुसकर अनर्थ किया था, वही वरिष्ठ शिक्षक आज बिहार के एक प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति हैं।"

—विकास कुमार झा

नारीशाला का गड़बड़झाला

राजस्थान सरकार ने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से बचाने में अपनी तत्परता दिखाने के लिए नारीशालाएं बनवा रखी हैं। लेकिन इन नारीशालाओं में औरतों के शोषण और दमन के अलावा और होता ही क्या है?

असहाय महिलाओं को समाज के क्रूर और लोलुप नरपिशाचों की पकड़ से सुरक्षित रखने के लिए बनायी गयी नारीशालाएं राजस्थान में अब आवासिनियों के देह-शोषण का केंद्र बनती जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा दोषियों को दंड देने के बजाय घटनाओं की लीपा-पोती करने पर अधिक जोर देते बताये जा रहे हैं। इससे भी अधिक खलनेवाली है, सतीकांड पर चीख-चीख कर आसमान सिर पर उठा लेने वाले महिला संगठनों की आश्चर्यजनक चुप्पी।

पिछले तीन माह के दौरान विभिन्न नारीशालाओं में घटी घटनाएं—जैसे भरतपुर और अजमेर की नारीशालाओं से आवासिनियों का भाग निकलना, जयपुर में आवासिनी इंदिरा की कथित आत्महत्या के बाद अब अजमेर की नारीशाला के ऐयाशी कांड की कलई खुलने से यह साबित हो गया कि महिलाओं के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले ये केंद्र अब अबलाओं के शोषण और शिकार के केंद्र बन गये हैं। अजमेर नारीशाला की आवासिनियों ने पूर्व अधिकारी हरमुख सिंह के खिलाफ खुलकर आरोप लगाया है कि उन्होंने दो साल तक नारीशाला को निजी ऐशगाह बनाये रखा तथा विरोध करने वाली आवासिनियों पर बर्बर अत्याचार किये-कराये।

ऐयाशी के रंग: नारीशाला को ऐशगाह में बदल डालने की हिमाकत वाले हरमुख सिंह असल में मात्र निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, परंतु अप्रैल '८६ से मई '८८ तक उन्हें नारीशाला के सहायक अधीक्षक का कार्यभार सौंप दिया गया। इन दो सालों के दौरान छह माह तक अधीक्षिका के लंबी छुट्टी पर रहने तथा दस माह तक स्थानांतरण के कारण नारीशाला के प्रभारी हरमुख सिंह ही बने रहे। अपने इस सोलह माह के एकछत्र राज में हरमुख सिंह ने पद की तमाम मर्यादाएं तोड़कर अपनी कामपिपासा को शांत करने का खुला खेल खेला।

नारीशाला में हरमुख सिंह की खास पसंदीदा थी एक सांवली, गूंगी-बहरी, मासूम लड़की, जिसे सब लोग 'काली गूंगी' कहते हैं। वे रोज नारीशाला के आंगन में मात्र कच्छा पहन कर धूप में लेट जाते और सारे नियमों व शर्म को ताक पर रख कर आवासिनियों के समक्ष अपनी देह का प्रदर्शन करते, काली गूंगी से बदन पर तेल मालिश करवाते तथा स्नान करने के बाद काली गूंगी के जरिये किसी मनपसंद आवासिनी को अलग से अपने कमरे में बुलाते, बहलाते-फुसलाते और राजी-गैरराजी अपनी कामवासना की पूर्ति करते थे।

असल में यह काली गूंगी ही हरमुख सिंह की राजदार भी थी। हरमुख सिंह समझते थे कि गूंगी होने के कारण यह किसी से कुछ कह नहीं सकेगी और उनके कुकर्मों पर परदा पड़ा रहेगा। पर एक दिन एक अन्य आवासिनी पुष्पा से झगड़ा होने पर काली गूंगी ने इशारों में सारा भेद खोल दिया। इस पर हरमुख सिंह ने काली गूंगी को बहुत पीटा। जब काली गूंगी गुस्से में आकर कुएं में कूदने की धमकी देने लगी, तो हरमुख ने उसकी टांगें पकड़कर कुएं मे लटका दिया। बाद में उसके हाथ पैर तख्त से बांधकर शरीर को जलती हुई सिगरेट से दागकर काली गूंगी को उसकी हिमाकत के लिए सजा तक दे डाली।

आईसी श्रीवातस्व

इसी मामले की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के सचिव आईसी श्रीवास्तव भी ३० अक्तूबर को अजमेर पहुंच गये।

हरमुख सिंह का वास्तविक नाम हरमुख लाल शर्मा है, पर नौकरी के दौरान उन्हें लगा कि नाम के साथ 'शर्मा' के स्थान पर 'सिंह' लगा लेने से रोब बढ़ जायेगा। उसी दिन से उन्होंने अपना नाम बदल डाला। भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के धनवाड़ा गांव के निवासी हरमुख पिछले १२ साल से अजमेर में जमे हुए हैं। इससे पहले वे भीलवाड़ा तथा भरतपुर में भी रह चुके हैं।

हरमुख की ऐयाशी व क्रूरता की कहानी पहली बार तब सामने आयी जब नारीशाला के अधिकारियों ने एक आवासिनी मीना के बयानों से घबरा कर आनन-फानन उन्हें कार्य-मुक्त कर नारीशाला से विदा करने की योजना बना डाली। ४ नवंबर को प्रातः १० बजे उन्हें सहायक अधीक्षिका प्रेमलता वर्मा और बाबू किफायतुल्ला खां की देखरेख में जोधपुर की बस आरएनपी १३४६ पर बिठा कर विदा कर दिया। इसी बस यात्रा में मीना ने दो पत्रकारों से मुलाकात के दौरान नारीशाला का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया।

पशुता का परदाफाश: बहुचर्चित नारीशाला से बाहर आये किस्सों के अनुसार यह सिलसिला शुरू होता है १६ अक्तूबर की रात से, जब रात के अंधेरे में नारीशाला में फैली अव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर नौ आवासिनियां भाग निकलीं। इनमें से पांच आवासिनियां सामने टेलीफोन एक्सचेंज भवन में, तीन रास्ते में और एक आवासिनी रेलवे स्टेशन पर पकड़ ली गयी। भागने वाली आवासिनियां थीं पुष्पा राजू, जूली, गणेशी, मीना, सीता, ममता, पुष्पा सिंधी, पुष्पा कैलाश और एक अन्य। इनमें से पुष्पा राजू को पुलिस दल ने स्टेशन पर ट्रेन में बैठे हुए पकड़ा था और उसे पहचानने वाला कांस्टेबिल था नरेंद्र सिंह। वह नारीशाला के पूर्व प्रभारी हरमुख सिंह का लड़का है और उस पर आरोप है कि वह भी नारीशाला में नियमों का उल्लंघन कर मालिश करवाने जाता था, इसीलिए उसने पुष्पा राजू को पहचान लिया।

उक्त वारदात की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के उप-निदेशक सुधीर कुमार २२ अक्तूबर को जयपुर से अजमेर पहुंच गये। जांच के दौरान उन्होंने सभी लड़कियों के बयान भी लिये। स्वभाव से तेज तर्रार और मुंहफट स्वभाव की मीना ने अपना मुंह खोल दिया। उसने नारीशाला में होनेवाली ऐयाशी तथा हरमुख सिंह के आतंक के साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा बयान कर डाला। लेकिन सुधीर कुमार ने संबंधित लोगों के खिलाफ जांच अथवा कार्यवाही के बजाय जल्द-से-जल्द मीना को नारीशाला से मुक्त करा देने की व्यवस्था कर डाली, ताकि बगावत की यह चिंगारी किसी को झुलसा न दे।

इसी मामले की जांच के लिए समाज कल्याण विभाग के सचिव आईसी श्रीवास्तव भी ३० अक्तूबर को अजमेर पहुंच गये। उनके आने की पूर्व सूचना पाते ही सहायक निदेशक गोविंद सिंह व जिला बाल अधिकारी जगदीश प्रसाद ओझा ने आवासिनियों को जैसे-तैसे मुंह बंद रखने के लिए फुसलाया। उनकी छोटी-मोटी मांगें मान ली गयीं, मीना से नारीशाला छोड़ देने का वायदा कराया गया। श्रीवास्तव के जाने के बाद मीना से अर्जी लिखवायी गयी कि वह अपने मां-बाप के पास जाना चाहती है। इस अर्जी पर सहायक निदेशक गोविंद सिंह ने सिफारिश लिखी तथा वे खुद जयपुर जाकर उपनिदेशक सुधीर कुमार से आदेश लिखवा कर ले आये। इसके बाद मीना को कानूनन उसके घर भेजा जाना चाहिए था, पर मीना जोधपुर

जाना चाहती थी। इसलिए कागजों में मीना को नारीशाला से मर्जी के मुताबिक कहीं भी जाने के लिए मुक्त कर दिया गया और सहायक अधीक्षिका प्रेमलता वर्मा की देखरेख में उसे बस में बिठाकर विदा कर दिया गया।

पर जाते-जाते भी मीना बस यात्रा में मिले पत्रकारों को नारीशाला की कहानी बयान कर ही गयी। इसके छपते ही फिर एक बार हड़कंप मच गया। इस हड़कंप से अधिकारियों की एकता तथा हौसला टूट गया। प्रेमलता वर्मा तथा हरमुख सिंह अलग-अलग खेमों में बंट गये। अब तक की सूचनाओं के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से अधिवक्ता वीर कुमार और बाल न्यायालय जूरी की सदस्या डा० के० टिक्कू ने नारीशाला के अंदर जाकर आवासिनियों के बयान लिये और ९ दिसंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के साथ संलग्न आवासिनियों के बयानों ने हरमुख सिंह के खिलाफ लगे आरोपों को सही ठहराया। इस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमरचंद भट्ट ने अलग से विस्तृत जांच शुरू कर दी। उनकी अंतरिम रिपोर्ट मिलने के पश्चात १८ दिसंबर को हरमुख सिंह को तथा उसके एक अन्य साथी रामबाबू मास्टर को निलंबित कर दिया गया। २० दिसंबर को समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक मोहन किशन व्यास ने रामगंज थाने में हरमुख सिंह तथा रामबाबू मास्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४ व ३७६ के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया।

आवासिनियों की आपबीती : हरमुख सिंह के कारनामों को उजागर करने में पहल की पुष्पा राजू नाम की आवासिनी ने। पुष्पा राजू ने अपने बयान में हरमुख सिंह पर बगीचे में कच्छा पहनकर लेटने, मालिश कराने, काली गूंगी का शरीर सिगरेट से दागने की घटनाओं की तसदीक करते हुए कहा कि हरमुख सिंह जब नारीशाला का साहब बना, तो काली गूंगी ने उसे (पुष्पा को) आफिस में पोछा लगाने के लिए बुलाया। पोछा लगाने में व्यस्त पुष्पा को हरमुख सिंह ने पीछे से दबोच लिया। कमरे की खिड़कियां पहले से ही बंद थीं। काली गूंगी ने दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिये। पुष्पा 'माताजी बचाओ, बचाओ' चिल्लाती रही और हरमुख सिंह ने पुष्पा के मुंह पर हाथ रखकर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार कर डाला। इसके बाद तो जब भी छुट्टी होती, हरमुख पुष्पा को कामवासना की पूर्ति के लिए आफिस में बुला लेता। मना करने पर काली गूंगी और हरमुख दोनों उसे पीटते। अपने बयान में पुष्पा ने हरमुख को मंजू तथा ऊषा नाम की आवासिनियों के साथ आफिस तथा गुसलखाने में बलात्कार करते हुए देखने का भी जिक्र किया है तथा कहा है कि हरमुख एक अन्य आवासिनी कमला को झूठी पेशी के बहाने नारीशाला के बाहर ले गया तथा अपने लड़के के साथ मिलकर उसके करंट लगाया। करंट लगने से कमला बेहोश हो गयी थी। बाद में उसे मर्जी के खिलाफ जबरन मां-बाप के साथ भेज दिया था। पुष्पा ने हरमुख पर शराब पीकर आने तथा नारीशाला में मीट पकाकर दावत उड़ाने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा उसने रामबाबू मास्टर पर आरोप लगाया है कि उसने ६० वर्षीय सावित्री मां के साथ गटर के पास बलात्कार किया।

एक अन्य आवासिनी मफीदा खातून ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि नारीशाला में आने के तीन दिन बाद हरमुख ने काली गूंगी के जरिये उसे आफिस में बुलाया तथा मफीदा का हाथ पकड़ कर अपने पैंट के ऊपर रखते हुए कहा, "तुम तो शादीशुदा हो, सब जानती हो," तथा जबरन चुंबन ले डाला। लेकिन वह किसी तरह हरमुख को धक्का देकर भाग निकली और इसके बाद कभी आफिस में अकेली गयी ही नहीं। पुष्पा की रूम पार्टनर ऊषा ने भी पुष्पा के बयान की तसदीक करते हुए कहा कि पुष्पा के साथ जो भी होता था, रात को मुझे बता देती थी। काली गूंगी का बयान सबको हैरान कर देने वाला था। उसने हरमुख सिंह की ऐयाशी को स्वीकारा, परंतु उसे अपना पति घोषित करते हुए हरमुख को बख्श देने की अपील की। हरमुख के खिलाफ कार्यवाही होने की सूचना पर वह बाकायदा आंसू बहाकर शोक प्रकट करती रही तथा कार्यवाही करने वालों को उसने गालियां भी दीं।

सत्यनारायण शर्मा

वीर कुमार

हरमुख के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप है इन हरकतों का विरोध करनेवाली आवासिनी धनलक्ष्मी को जबरन पागलखाने भेज देने का। अखबारों में इस कांड के प्रकाश में आने के बाद धनलक्ष्मी ने मथुरा से पत्र लिखकर सारी घटनाओं की तसदीक की तथा आपबीती का जिक्र करते हुए उसने बताया कि २६ मार्च को हरमुख ने सुबह साढ़े दस बजे उसे आफिस में बुलाया और कहा, "कल मैं छुट्टी ले रहा हूं, कल त्यौहार भी है, बताओ स्पेशल चीज क्या बनाओगी?" धनलक्ष्मी ने खीर-पूड़ी बनाने का प्रस्ताव किया। इसके बाद काली गूंगी ने धनलक्ष्मी के सिर पर हाथ फिराकर अपना प्यार जाहिर किया। हरमुख सिंह बोला, "देखो, काली गूंगी तुम्हें कितना चाहती है।" धनलक्ष्मी ने कहा कि कालीगूंगी की नीयत मेरी हेयरपिन और चूड़ियों पर बिगड़ी हुई है, कहती है, जाओ तब मुझे दे जाना। इस पर हरमुख सिंह ने धनलक्ष्मी का हाथ पकड़ कर कहा, "भगवान ने तुम्हें शक्ल ही ऐसी दी है जिसे देखकर किसकी नीयत न बिगड़े?" तभी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आते ही धनलक्ष्मी हरमुख को गालियां देने लगी। इस पर हरमुख ने धनलक्ष्मी को घसीटवाकर कमरे से निकलवा दिया। इसके बाद २८ मार्च को यह कहकर कि इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, धनलक्ष्मी को किफायत खां तथा बसंती बाई की देखरेख में जयपुर के पागलखाने में भर्ती करवा दिया। पागलखाने की पीड़ा भोग कर साढ़े तीन महीने बाद २० जुलाई को धनलक्ष्मी इस प्रमाण पत्र के साथ वापस आ गयी कि वह पागल नहीं है। इससे पूर्व २४ मार्च को हरमुख ने मफीदा पर हाथ डालने का असफल प्रयास किया था जिसकी शिकायत मफीदा ने लौटकर धनलक्ष्मी से की। इस पर धनलक्ष्मी ने ही एक शिकायती पत्र लिखकर सभी पीड़ित आवासिनियों से हस्ताक्षर करा या अंगूठे लगवा कर नारीशाला के कर्मचारियों को दिया। हरमुख सिंह ने पता चलते ही शिकायती पत्र को फाड़ डाला तथा धनलक्ष्मी के साथ गाली-गलौच कर उसे आतंकित करने की कोशिश की थी। पागलखाने की यंत्रणा भोग सही सलामत लौट आने पर लक्ष्मी ने नारीशाला के नरक से पीछा छुड़ाने में ही अपनी भलाई समझी। इस बीच पागलखाने में वह एक बच्ची की मां भी बन चुकी थी।

एक अन्य आवासिनी भगवती को लेने उसके मां-बाप जब नारीशाला पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उसे पहले ही कोई नेपाली युवक लेकर चला गया। भगवती के मां-बाप की शिकायत है कि हरमुख की 'सेवा पूजा' के बदले यह काम किया था। ऐसे ही न जाने कितने ही किस्से नारीशाला की आवासिनियों के सीनों में दफन हैं जो विस्तार से जांच के दौरान सामने आयेंगे।

पाक-साफ कौन ? : पता चला है कि हरमुख सिंह की हौसला-अफजाई तब से शुरू हुई जब एक मजिस्ट्रेट ने उसे अपनी ससुराल के ड्राइवर से किसी आवासिनी की शादी करा देने के लिए कहा। हरमुख सिंह ने उस समय पुष्पा राजू के साथ ही उस ड्राइवर की शादी कराने की कोशिश की थी और विभाग की मंजूरी लेने के लिए खुद दो बार जयपुर भी गया था। परंतु पुष्पा के नाबालिग होने के कारण हरमुख को अनुमति नहीं मिली थी। इसी दौरान जिला बाल अधिकारी से भी उसके संबंध प्रगाढ़ हो गये थे। इन्हीं संबंधों का लाभ उठाकर वह नारीशाला में स्थानांतरण के बाद भी बाल अधिकारी जगदीश प्रसाद ओझा के साथ शराब पीकर नारीशाला में आ धमकता था। दूसरी ओर ओझा पर आरोप है कि वे लंबे समय तक नारीशाला के प्रभारी रहे और हरमुख की करतूतों को जानते-बूझते नजरअंदाज करते रहे। बहरहाल, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होते ही हिरासत में लिये जाने की आशंका से घबराकर हरमुख सिंह भूमिगत हो गया। उसकी तरफ से उसके वकील सत्यनारायण शर्मा ने शैल कुलश्रेष्ठ और बालमुकन्द शर्मा के साथ मिलकर कोर्ट में जमानत की अपील दायर कर दी। जब इस संवाददाता ने हरमुख सिंह से मिलना चाहा, तो उसके लड़के तथा वकील से ही मुलाकात हो सकी। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हरमुख सिंह का एक लड़का उसी थाने में काम करता है जिसमें उसके

खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा दूसरा लड़का उस वकील का सहायक है जो जमानत का केस लड़ रहा है। अपनी जमानत की अपील में हरमुख सिंह ने सारे मामले को 'राजनीति से प्रेरित तथा बदनाम करने के लिए गढ़ी गयी साजिश' कहा है।' उसके वकील सत्यनारायण, एडवोकेट वीर कुमार (जो नवभारत टाइम्स के संवाददाता भी हैं) पर ब्लैकमेल करने तथा अनुचित मांगों की पूर्ति न होने पर बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाते हैं। सत्यनारायण सफाई में कहते हैं कि हरमुख सिंह के लड़के नरेंद्र ने जब पुलिस दल के साथ पुष्पा राजू को स्टेशन पर पकड़ा था, तब पुष्पा राजू ने उसे तथा उसके बाप को देख लेने की धमकी दी थी। सारी कहानियां उसी धमकी को देखने के लिए गढ़ी गयी हैं। उल्लेखनीय है कि पुष्पा राजू तीन वर्ष पूर्व १७ जनवरी, १९८६ को चोरी के आरोप में कोर्ट में पेश की गयी थी, उस समय उसकी उम्र मात्र १३ वर्ष थी। कोर्ट में पुष्पा राजू ने उलटे अपने सेठ मनमोहन गुप्त पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। परंतु मेडिकल रिपोर्ट में उसे 'यौन संबंधों का आदी' पाया गया। उस समय भी पुष्पा राजू की पैरवी एडवोकेट वीर कुमार ने ही की थी।

पुष्पा के चरित्र को संदेहास्पद और इस मामले में वीर कुमार और पुष्पा की मिली भगत बताते हुए सत्यनारायण कहते हैं कि पिछले केस में सदमे से सेठ मनमोहन गुप्त की मृत्यु ही हो गयी थी। यह संयोग भी कम दिलचस्प नहीं है कि हरमुख सिंह के स्थानांतरण पर जाने के बाद जिन प्रेमलता वर्मा ने सहायक अधीक्षिका के रूप में कार्यभार संभाला है, वे स्वयं दो वर्ष पूर्व इसी अजमेर नारीशाला में अधीक्षिका थीं। उनके खिलाफ भी आवासिनियों को अफसरों की काम-पिपासा की पूर्ति के लिए नारीशाला से बाहर भेजने, अपने भाई को अधीक्षिका निवास में रखने तथा दोस्तों के साथ शराब पीकर नारीशाला में उत्पात मचाने की छूट देने जैसे गंभीर आरोप थे। तत्कालीन विभागीय मंत्री छोगाराम बाकोलिया ने स्वयं विशेष छापा मार कर प्रेमलता वर्मा को रात भर चार आवासिनियों के साथ नारीशाला से गायब रहने के आरोप में मुअत्तल कर दिया था। अब उन्हें ही पदावनत कर इस नारीशालौ का कार्यभार दुबारा सौंपा गया है।

राजेंद्र सिंह

सिंह जांच पूरी होने से पूर्व कोई भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं हैं।

प्रताड़ना जारी : कानूनी स्थिति का खुलासा करते हुए वीर कुमार बताते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा ३७६ सी में हुए संशोधन के मुताबिक नारी सुरक्षा गृह अथवा नारी कल्याण केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा, कार्यरत अथवा संरक्षित महिला के साथ उसकी इच्छा से यौन संबंध स्थापित करना भी अपराध है और इसके लिए कम-से-कम पांच साल की सजा का प्रावधान है। वे यह भी बताते हैं कि भरतपुर से संबंधित एक मुकदमे का फैसला करते हुए उच्च न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिये थे कि महिला संस्थाओं में महिलाओं को ही प्रभारी रखा जाये।

अजमेर के रामगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट की जांच थानेदार राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। सिंह जांच पूरी होने से पूर्व कोई भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं हैं।

दूसरी ओर विभाग के अधिकारी यह जांच करने में जुटे हुए हैं कि नारीशाला के अंदर की कहानी सीखचों को पार कर अखबारों तक कैसे पहुंची। आफिस के जिन कर्मचारियों पर खबरें लीक करने का शक है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आवासिनियों के भागने की जिम्मेदारी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामदुलारी पर डालकर उसका स्थानांतरण कर दिया गया है, जबकि वह उस दिन छुट्टी पर थी।

—धीरज कुलश्रेष्ठ

करोना का नाम, आराम की नयी धूमधाम!

रु. 78.00*
स्पोर्टिफ़
रु. 78.00*
सिल्वर स्ट्रीक
रु. 83.00*
रोवर I
रु. 91.00*
रोवर II
ACTIF
रु. 91.00*
ऐक्टिफ़
PANTHER
रु. 67.00*
पैन्थर

* अधिकतम सूचित खुदरा कीमत.
स्थानीय कर अलग.

सर्वाधिक आराम के लिए सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी

C.S.C. Carona

CHAITRA-B CL 490 HIN

सभी करोना शॉप तथा प्रमुख फुटवेअर स्टोर्स में उपलब्ध.

जनता दल का अंतर्कलह

नये दल के गठन के आसार

जनता दल के गठन के बाद राजस्थान के जोधपुर शहर में दल के आला नेताओं ने गत १८ दिसंबर, १९८८ को एक आम सभा का आयोजन किया। शासक दल के असंतुष्ट नेताओं ने इस आयोजन का मन-ही-मन स्वागत किया। आम सभा में लगभग पचास हजार लोग शामिल हुए। पर इस सभा से पूर्व जोधपुर सर्किट हाउस में जो नाटक हुआ, उससे कांग्रेस-इ के विकल्प का दावा करने वाले जनता दल की राजस्थान शाखा की सफलता पर प्रश्नचिह्न लग गया। दरअसल, जोधपुर में जनता दल के सम्मेलन के लिए फैसला दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संचालन समितियों के गठन के पूर्व राजस्थान के बीकानेर सम्मेलन के दौरान लिया गया था। बाद में दल की राष्ट्रीय कार्यसमिति में प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा व प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह काल्वी को राष्ट्रीय कार्यसमिति में शामिल नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि इन दलों के वही युवा विधायक और कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी में जुटे जो देवीलाल का समर्थन कर रहे थे।

मिर्धा और काल्वी के प्रभाव क्षेत्र, जोधपुर में सम्मेलन की सफलता उनके सहयोग के बिना कठिन थी। नतीजतन प्रदेश लोकदल के नेता नाथूराम मिर्धा को देवीलाल के इशारे पर पटकी मारने वाले विधायक मोहन प्रकाश ने आला नेताओं को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। फिर बुजुर्ग नेताओं को मनाने के लिए एक प्रदेश स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसमें मिर्धा, काल्वी के अतिरिक्त चौधरी कुंभाराम आर्य, मोहन छगाणी व दौलत राम सारण को शामिल किया गया। यह भी घोषणा की गयी कि राजस्थान में जनता दल के बारे में तमाम निर्णय यही समिति लेगी।

इसके बाद असंतुष्ट नेता १६ दिसंबर, १९८८ की शाम जोधपुर रवाना हुए। जोधपुर सर्किट हाउस में टिके पूर्व लोकदल विधायक एवं नवगठित दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जगतपाल सिंह दायमा के साथ हादसा हो गया।

दायमा के अनुसार १६ दिसंबर को दोपहर डेढ़ बजे हरे रंग का झण्डा फहराये एक जीप में सवार दस युवक सर्किट हाउस पहुंचे। इन लोगों ने हरियाणा के मंत्री बलबीर सिंह व हरि सिंह के कमरों के बाहर एकत्र होकर 'देवीलाल मुर्दाबाद' के नारे लगाये। इन्हीं में से कुछ युवक विधायक दायमा के पास पहुंचे और उनसे नाम पूछ कर हाथापाई की। उनके अनुसार बेशुमार गालियों के साथ उक्त लोगों ने उन्हें देवीलाल का चमचा कहा तथा धमकी दी कि वे जोधपुर छोड़कर चले जायें वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा।

दायमा का आरोप था कि इस पूरे कांड के पीछे नाथूराम मिर्धा का हाथ था। उनका कहना था कि मिर्धा ने बौखलाकर उन्हें प्रताड़ित करने की तिकड़म रची है। गौरतलब बात यह थी कि दायमा जब पत्रकारों को आप बीती सुना रहे थे, तो उन्हीं के साथी जनता दल के नेता माणक सुराणा व नारायण राम बेड़ा खामोश थे।

नाथूराम मिर्धा

कल्याण सिंह काल्वी

इसी रात जोधपुर पहुंचे मिर्धा ने अगले दिन बयान जारी कर विधायक जगतपाल सिंह दायमा के साथ घटी घटना से अपना संबंध होने से इनकार किया। बहरहाल असंतुष्ट नेताओं के राजी होने से लगभग छह लाख की जनसंख्या वाले जोधपुर शहर में मचास हजार के लगभग लोगों ने जनता दल के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं को सुना। इसी दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने जोधपुर में पत्रकारों के समक्ष अपनी हरियाणवी अदा में बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। चौधरी देवीलाल ने पत्रकारों के बीच फरमाया, ''मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था, पर सुप्रिया की मौत के मामले पर लोकसभा में बलराम जाखड़ ने जिस तरह से शोर मचाया; उसे देखते हुए मैंने 'उससे' (जाखड़ से) चुनावी मैदान में निपटने का मन बना लिया है।'' चौधरी देवीलाल का कहना था कि केन्द्रीय भू परिवहन मंत्री राजेश पायलट के खिलाफ वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्य अवतार सिंह और केन्द्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के विरुद्ध कृपा सिंह पूनिया को प्रत्याशी बनायेंगे।

इस बयान पर मिर्धा व काल्वी ने सीधे कुछ नहीं कहा, पर राजस्थान में विपक्षी राजनीति में त्रिमूर्ति के रूप में पहचाने जाने वाले नेताओं में से एक भाजपा नेता शेखावत चुप न रह सके। शेखावत ने २१ दिसंबर १९८८ को बयान जारी कर चौधरी देवीलाल द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशियों की इकतरफा घोषणा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपने बयान में उन्होंने इस घोषणा को राजस्थान के गौरव व सम्मान के विरुद्ध बताते हुए स्पष्ट किया कि ''हम राजस्थान को हरियाणा की 'जागीर' नहीं बनने देंगे।''

भैरों सिंह शेखावत

''हम राजस्थान को हरियाणा की 'जागीर' नहीं बनने देंगे।''

भाजपा नेता शेखावत के इस बयान पर जनता दल में शामिल त्रिमूर्ति के बाकी सदस्य यानी मिर्धा व काल्वी ने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि लोकदल-ब के पूर्व महासचिव सुखदेव आर्य ने बयान जारी किया। यह बयान सुलह सफाई का एक जरिया बने, इसी अंदाज से जारी किया गया। आर्य का स्पष्टीकरण था कि भाजपा नेता भैरों सिंह शेखावत ने चौधरी देवीलाल के भाषण की मूल भावना को समझने में गलती की है। उनका कहना था कि चौधरी ने पायलट, जाखड़ और बूटा सिंह जैसे 'बाहरी' नेताओं को राजस्थान से सांसद बनाकर भेजने पर एतराज करते हुए कहा था कि इस बार भी अगर राजस्थान से ये नेता खड़े हुए, तो उनके विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। आर्य ने शेखावत को १९८४ की याद दिलाते हुए भाजपा द्वारा विपक्ष से अलग जाकर चुनाव लड़ने की गलती न दोहराने की चेतावनी दी। फिर इस बयान की प्रतिक्रिया में भाजपा के प्रदेश मंत्री दामोदर शर्मा ने बयान जारी किया। इस बयान में भाजपा की वस्तुस्थिति १९८४ में क्या थी, इसे स्पष्ट किया गया था। उनका कहना था कि भाजपा ने १९८४ में संसद की १५ सीटों पर अपना दावा पेश किया था, परंतु लोकदल एवं ज़नता पार्टी दोनों दल भारतीय जनता पार्टी को किसी भी स्थिति में दस सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं थे। परिणामस्वरूप विपक्ष का तालमेल नहीं हुआ और भाजपा ने प्रदेश की कुल २५ सीटों में से २३ सीटों पर चुनाव लड़ा तथा १५ सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही। उनके अनुसार इन पन्द्रह सीटों में केवल सीकर निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर हर जगह लोकदल व जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई थीं।

बहरहाल, इन बयानबाजियों के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनता दल के जोधपुर सम्मेलन में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह को प्रभावित करने के लिए मिर्धा और काल्वी के युवा अनुयायियों ने काफी दौड़धूप की। दल की कार्यसमिति के गठन को लेकर इन युवा अनुयायियों ने सिंह से इतने सवाल किये कि वे बरबस कह पड़े, ''मैं तो एक साल पहले ज्यादा खुश था।''

इस वास्तविकता को शेखावत के बयान से जोड़ने के बाद एक नयी स्थिति राजस्थान की राजनीति में उजागर हुई है। यह स्थिति भाजपा नेता शेखावत की अपनी पार्टी से नाराजगी और मिर्धा-काल्वी नेतृत्व के विरुद्ध जनता दल में असंतोष के साथ विपक्षी त्रिमूर्ति के पुनः एक होने की ओर इशारा करती है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में जनता दल के सामने इस त्रिमूर्ति से समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। वैसे चौधरी देवीलाल की चली, तो राजस्थान में त्रिमूर्ति एक प्रान्तीय दल का गठन कर सकते हैं। **—ओम सैनी**

शिवसेना का तृतीय अधिवेशन

आम चुनाव जीतने का रिहर्सल

पिछले ३०-३१ दिसंबर को पुणे में हुए शिवसेना के तीसरे अधिवेशन ने महाराष्ट्र कांग्रेस की नींद हराम कर दी है। आखिर उस अधिवेशन में क्या था जो सत्तारूढ़ दल के लिए जबर्दस्त चुनौती बन गया?

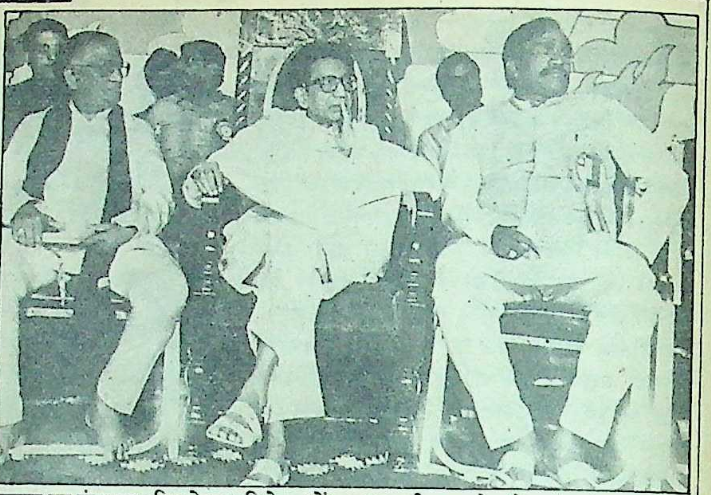

चुनाव का इंतजार : शिवसेना अधिवेशन में दत्ता साल्वी, ठाकरे और चंद्रकांत पडवल

जब समूचा देश नये वर्ष का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था, बंबई से १६६ किमी दूर २० लाख की आबादीवाला नगर पुणे, जिसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, कुछ और ही रंग में डूबा हुआ था। शहर की सड़कों-गलियों में केसरिया बानों, झंडों और पताकाओं की बहार-सी छायी हुई थी। राह चलते स्त्री-पुरुष तथा मैदानों-सड़कों पर खेल रहे बच्चे एकबारगी 'गर्वानि सांगा आम्ही हिंदू आहेत' (गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं) के नारे लगाते हुए उस चहल-पहल को बढ़ाते जा रहे थे।

हमेशा, हर ओर से हरा-भरा और बीच में धूसर दिखायी देनेवाला पुणे अब केसरिया रंग में नहाकर शिवसेना के तीसरे अधिवेशन (३० एवं ३१ दिसंबर '८८) का स्थल बन गया था। अधिवेशन में भाग लेने के लिए समूचे महाराष्ट्र से ४५ हजार से अधिक प्रतिनिधियों के अलावा १० हजार से अधिक पर्यवेक्षक समूचे भारत से आये हुए थे। इनमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी, जिनके साथ शिवसेना का अगले आम चुनाव के लिए चुनावी गठबंधन अब निर्णायक दौर में है। इसके साथ ही वसंत दादा पाटील का परोक्ष आशीर्वाद भी उनके साथ था, जिन्हें पिछले महीने ही शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने 'किसानों का सच्चा हितैषी' होने का फतवा देकर 'कांग्रेस के अंदर अपमान भरी जिंदगी' से विद्रोह कर शिवसेना से आ जुटने का आमंत्रण दे दिया था। अधिवेशन के दौरान भी वे अपने इस आमंत्रण को दुहराये बिना नहीं रह सके थे।

'इमेज' बदलने की कोशिश : इस अधिवेशन में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने विशेष तवज्जह शिवसैनिकों की 'गुंडों' के रूप में बनी 'इमेज' को तोड़कर 'समाजसेवी कार्यकर्ता' की छवि निखारने पर दी। लगभग सवा दो दशक पूर्व बंबई के एक दैनिक समाचार पत्र में कार्टूनिस्ट का काम करने वाले बाल ठाकरे ने महानगर के उन बेरोजगार मराठी युवकों को लेकर शिवसेना का गठन किया था, जो बंबई के बाहर से आये दक्षिण भारतीयों, गुजरातियों तथा उत्तर भारतीयों के व्यावसायिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व के कारण अपने आपको पिछड़ा, निर्धन तथा बेरोजगार महसूस कर रहे थे। अनुशासन तथा जांबाजी के लिए मशहूर मराठियों की इस भावना को उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साथ जोड़कर, उनके नाम पर शिवसेना का नामकरण कर, बडी जल्दी बेरोजगार उत्साही मराठी युवकों की एक फौज खड़ी कर दी, जो बड़ी तेजी से बबई के मराठी-बहुल इलाकों से फैलती हुई उपनगरों और ग्रामीण अंचलों तक पहुंच गयी। तब शिवसेना के पास कोई विशेष तथा दूरदर्शी कार्यक्रम न होने के कारण उनकी इमेज 'गुंडा-फौज' के रूप में इसलिए बन गयी, कि वे बल और डंडे के जोर पर झोपड़-पट्टियां स्थापित करते और अवैध निर्माण कर मराठी लोगों को कब्जे दिलाते थे। इसी दौर में शिवसैनिकों की सशस्त्र झड़पें भी गैरमराठियों से होती रहीं। उन्होंने धमकियों तथा आतंक का सहारा लेकर उद्योगपतियों को अपने कारखानों में मराठियों को काम देने के लिए इतना बाध्य किया कि बहुत-से गुजराती तथा दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों ने अपना डोर-डम्पर उठाकर अपने गृहराज्यों को कूच कर दिया।

डा० दत्ता सामंत की यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शिवसेना ने समानांतर मजदूर यूनियनों का गठन कर जो अपनी विजय-पताकाएं छोटे-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों से लेकर होटलों-रेस्तरों तथा दुकानों पर लगानी शुरू कीं, उसे तत्कालीन कांग्रेस प्रशासन ने देखते हुए भी इसलिए अनदेखा किया, क्योंकि डा० दत्ता सामंत के जिस प्रभाव को वे रोकने में असमर्थ थे, उसे शिवसैनिक बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहे थे।

इस तरह अपनी बढ़ती ताकत और प्रभाव को बाल ठाकरे तथा शिवसेना ने बंबई नगर महापालिका के चुनाव जीतने में लगाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से संपर्क भी साधे, लेकिन शीघ्र ही बाल ठाकरे ने महसूस किया कि अगर शिवसेना को प्रभावशाली बनाना है, तो उसे बंबई, ठाणे तथा पनवेल के लगभग ३०० किमी क्षेत्र से बाहर निकलकर समूचे महाराष्ट्र में फैलाना होगा। बंबई में १९८४ में हुए सांप्रदायिक दंगों ने बाल ठाकरे को अपने पूर्व नारे 'आमची मुंबई आमची मराठी' की जगह 'हिंदुत्व की रक्षा' का नारा लगाने के लिए प्रेरित किया। इस नारे का परिणाम उन्हें १९८७ में गुजराती बहुल विलेपार्ले में हुए विधानसभाई उपचुनाव में मिला, जब शिवसेना उम्मीदवार डा० रमेश प्रभु ने शिवसेना के 'हिंदुत्व की रक्षा' तथा 'गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं' नारे के बल पर कांग्रेसी उम्मीदवार प्रभाकर कुंटे को बुरी तरह से हरा दिया। इस चुनाव-प्रचार में बाल ठाकरे ने गुजरातियों से, शिवसेना के साथ चली आ रही पुरानी दुश्मनी भूल जाने का आह्वान किया था। गुजरातियों ने बाल ठाकरे और शिवसेना में आये उस मानसिक बदलाव को तहेदिल से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वे उनके 'हिंदुत्व समर्थक' नारों के पक्षधर थे। इस बदली हुई छवि के साथ शिवसेना ने मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रवेश किया और मुसलमान-बहुल आबादी वाले औरंगाबाद नगर महापालिका का चुनाव जीत लिया, जहां तब तक कांग्रेस का वर्चस्व था। इसके बाद हमेशा शांत रहनेवाला औरंगाबाद सांप्रदायिक तनावों का गढ़ बन गया, जिसके लिए शिवसेना तथा कांग्रेस एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन कांग्रेस, शिवसेना से न तो औरगाबाद नगर महापालिका का गढ़ जीत सकी, न ठाणे और बंबई का।

महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ते प्रभाव से प्रेरित होकर शिवसेना ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह दो वर्ष पूर्व अपना भी वार्षिक अधिवेशन शुरू किया। पहला अधिवेशन औरंगाबाद और दूसरा महाड में हुआ। ३०-३१ दिसंबर, ८८ को पुणे में हुआ शिवसेना का तृतीय अधिवेशन, कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, प्रमुख शहरों की नगरमहापालिकाओं, जिला परिषदों के अलावा महाराष्ट्र के आम चुनाव को जीतने की पृष्ठभूमि बनाना। इसीलिए इस अधिवेशन को 'शिवसेना के चुनावी रिहर्सल' की संज्ञा दी गयी।

आयोजन की भव्यता : 'शोमैनशिप' (प्रदर्शन की दक्षता) तथा भव्यता दिखाने के आदी बाल ठाकरे ने इस (तृतीय) अधिवेशन के आयोजन में भव्यता के सारे कीर्तिमानों को तोड़ दिया। क़ोथरूड (पुणे) में स्थापित छत्रपति शिवाजी की विशालकाय प्रतिमा के पूजन-समारोह के समय सलामी के लिए कोल्हापुर से पांच ऐतिहासिक तोपें विशेष रूप से लायी गयी थीं। पूजन के बाद शांति के प्रतीक कबूतरों तथा केसरिया गुब्बारों से समूचे आसमान को पाट दिया गया था। पारंपरिक वेशभूषा में सुहागिनों तथा कुंवारी कन्याओं को बाल ठाकरे की आरती के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। उन्हें जो मालाएं पहनायी गयीं, वे ६५ किग्रा वजन की थीं।

कोथरूड से अधिवेशन स्थल (एसवी कालेज ग्राउंड, जिसका नाम अधिवेशन के लिए 'क्रांतिवीर चापेकर बंधु पुण्य भूमि, रखा गया था) तक बाल ठाकरे का जो जुलूस निकला, उसमें उनकी कार के आगे-पीछे सौ मोटर साइकिलों पर सवार केसरिया साफा बांधे शिवसैनिक 'फ्लाइंग स्क्वाड' (उड़ाका दल) की तरह चल रहे थे। कार के पीछे अनगिनत कारों, ट्रकों, मोटर-साइकिलों तथा स्कूटरों का काफिला चल रहा था। विभिन्न स्थानों से आये लोकनर्तकों-गायकों की टोलियां नाचती-गाती-बजाती चल रही थीं। जुलूस में ऐसे बालक-बालिकाओं की संख्या भी अनगिनत थी जो या तो बाल ठाकरे के रंगीन चित्र लटकाये हुए थे या माथे पर 'गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं', लिखा केसरिया पट्टा लगाये हुए थे। सड़कों-गलियों के दोनों ओर लगे असंख्य पोस्टरों में बाल ठाकरे के चित्र के नीचे उन्हें 'हिंदू हृदय सम्राट' की उपाधि से अलंकृत किया गया था, जो इसके पहले सिर्फ स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए प्रयुक्त होती थी।

महाराष्ट्र के तमाम जिलों, तालुकों तथा गांवों से ज्योति लाकर अधिवेशन स्थल पर प्रज्ज्वलित की गयी थी। अधिवेशन-स्थल पर शिवाजी के अलावा जनरल अरुण वैद्य (जिनकी आतंकवादियों ने पुणे में हत्या कर दी थी) की प्रतिमाएं लगायी गयी थीं तथा विभिन्न स्थानों पर बने छह द्वारों के नाम 'संत गाडगे बाबा', 'अन्ना भाऊ साठे', 'सावित्री बाई फुले', 'डा० हेडगेवार', 'जनरल अरुण वैद्य' तथा 'हिंदू शक्ति' रखे गये थे। कांग्रेस अधिवेशनों की शैली में ५० स्टालोंवाली एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था तथा मंच पर प्रख्यात चित्रकार मोहन वाघ द्वारा मजदूर-किसान तथा ज्वार की फूली हुई सुनहरी बालियों के विशेष रूप से तैयार रंगीन चित्र भी लगाये गये थे। अधिवेशन के बाद जो रैली निकाली गयी, उसमें तीन लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था।

एक ही नारा : 'गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं' की पट्टी लगाये हुए एक कार्यकर्ता

हमले और फिकरे : अपने विरोधियों पर आक्रामक हमले और पैने व्यंग्य से सराबोर फिकरे कसने में अद्वितीय बाल ठाकरे ने जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार पर करारे हमले किये, वहीं राजीव गांधी से लेकर हर बड़े नेता पर अपने पैने व्यंग्यबाण भी बरसाये। उन्होंने चुटकी ली, "गांधीजी ने गांधी टोपी चलायी और नेहरूजी ने नेहरू जैकेट, तो क्या अब राजीव गांधी राजीव पाजामा चलायेंगे?" शरद पवार पर हमले का कारण था, शिवसेना अधिवेशन से एक सप्ताह पूर्व विधानसभा अधिवेशन (नागपुर) में शरद पवार द्वारा शिवसेना की जड़ें उखाड़ने के बारे में किया गया आह्वान, जिसने शिवसेना प्रमुख को गुस्से में भर दिया था। इत्तिफाकं से उसी दौरान आतंकवादियों के संभावित हमले की खबर मिल जाने के कारण वे आम सभा में भाषण नहीं कर सके थे। ठाकरे ने शरद पवार पर आरोप लगाया, "उन्होंने (मुख्य मंत्री की कुरसी हासिल करने के लिए) महाराष्ट्र से कांग्रेस चुनाव-कोष के लिए १५०० करोड़ रु० एकत्र कर देने का वायदा राजीव गांधी से किया है। उन्हें इंका हाईकमान ने महाराष्ट्र से शिवसेना के सफाये का काम सौंपा है। मुगल भी महाराष्ट्र से शिवाजी की सत्ता को खतम करने का संकल्प लेकर यहां आये थे, लेकिन उन्हें मुहकी खानी पड़ी। यही हाल शरद पवार का भी होगा। शिवसेना के धन के स्रोतों का पता लगाने के बजाय, बेहतर है, वे कोंकण के समुद्रतटीय क्षेत्रों पर अपना ध्यान लगायें जहां तस्करों का साम्राज्य है और वे उसे पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं।" बाल ठाकरे यह भी कहने से नहीं चूके, "अगर चुनाव में शिवसेना जीत गयी, तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार शिवसेना में भी शामिल हो जायें।".

असली मुद्दा : बाल ठाकरे ने अधिवेशन में आर्थिक नीतियों या दूसरी योजनाओं को दरकिनार रख 'हिंदुत्व की रक्षा' और 'हिंदू राज' को ही प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने 'माया' को बतलाया, "मैं इन सब बातों, वादों-घोषणाओं में इसलिए विश्वास नहीं करता कि ये सब जनता को भरमाने के राजनीतिक हथकंडे हैं। शिवसेना के सत्ता में आने के तुरंत बाद इन समस्याओं का हल अपने आप ही निकल आयेगा। पहले हम रोटी-कपड़ा-मकान पर ध्यान देंगे। बिल्डर माफिया के कब्जे से जमीन मुक्त कराकर सहकारी समितियों को मकान बनाने का दायित्व सौंप देंगे। सभी उपभोक्ता सामानों के दाम तय कर देंगे और दुकानदारों को उन्हीं कीमतों पर सामान बेचने पड़ेंगे। लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी लंबे समय से खतरे में पड़े हिंदुत्व की रक्षा करने की है। मैंने सबसे कह दिया है और आम आदमी से अनुरोध भी करता हूं कि वे धूमधाम से शिवाजी जयंती, गणेश चतुर्थी आदि त्यौहारों को मनायें तथा हिंदू तीर्थों एवं मंदिरों की रक्षा करें।"

बाल ठाकरे सिर्फ भाजपा आदि कुछ संगठनों से ही चुनावी तालमेल के पक्ष में हैं। उनका कहना है, "शिवसेना ज्यादा राजनीतिक दलों के साथ चुनावी तालमेल में इसलिए रुचि नहीं रखती कि बाद में कुरसी और पद को लेकर पार्टियां आपस में लड़ने लगती हैं और मूल उद्देश्य से पीछे हट जाती हैं। आप उन लोगों (जनता दल) को ही देख लीजिए, वर्चस्व की इसी बीमारी के कारण वे मन से एकजुट नही हो पा रहे हैं।"

इंका की बेचैनी : दो वर्ष पहले जब शिवसेना ने अपना दायरा महाराष्ट्र के भीतरी क्षेत्रों में भी बढ़ाने की घोषणा की थी, तो इंका तथा वामपंथी दलों ने बाल ठाकरे की खिल्ली उड़ायी थी। लेकिन वही इंका तथा वामपंथी दल इस अधिवेशन में प्रदर्शित शिवसेना की भीतरी पहुंच से अपने लिए कई खतरे महसूस करने लगे हैं। 'हुतात्मा चापेकर बंधु पुण्य भूमि' में अपूर्व शक्ति-प्रदर्शन के साथ शिवसेना द्वारा दी गयी चुनौती कांग्रेस-इ का सरदर्द बन गयी है। शिवसेना अधिवेशन में, जब इंकाइयों ने मतदाता सूची में शामिल होने के उत्साहवाले १८ से २१ वर्ष तक की आयु के युवक-युवतियों का लहराता समुद्र देखा और उनका 'जय भवानी, जय शिवाजी' का तुमुल जयनाद सुना, तो उनका माथा ठनक गया। शिवसेना की इस विशाल सभा में औपचारिक रूप से शुरू की गयी उसकी किसान शाखा, 'शेतकारी सेना' में ग्रामीण युवकों का उत्साह देखकर तो एक इंकाई के मुंह से बरबस निकल ही पड़ा, "अगर ये इसी हौसले के साथ आगे बढ़े, तो विधानभवन पर केसरिया झंडा फहराने से इन्हें कौन रोक सकेगा?"

यह रपट लिखे जाने तक कांग्रेस-इ इस चुनौती का माकूल जवाब अपने औरंगाबाद सम्मेलन (१६ जनवरी) में देने की तैयारी में जुटी हुई थी। एक कालेज की छत से शिवसेना का अधिवेशन देख चुके पुणे के इंकाई मेयर अंशुक काकड़े ने अपनी बेचैनी को ढंकते हुए दावा किया, "शिवसेना के बहुतेरे सदस्य अब कांग्रेस में आने लगे हैं, शरद पवार के मुख्यमंत्री बनने की बदौलत औरंगाबाद सम्मेलन में यह साफ दिखायी देगा।"

—बंबई ब्यूरो

किसकी दिल्ली, किसकी शान ?

देश की राजधानी दिल्ली को बेहतर (अधिक स्वच्छ और सुंदर) बनाने के धुआंधार प्रचार के साथ गत दिसंबर में एक पखवारे का अभियान चलाया गया। जब सिर्फ अखबारी प्रचार पर लाखों रुपए खर्च हुए, तो अभियान में करोड़ों रुपए लगे ही होंगे। लेकिन क्या दिल्ली बेहतर बन गयी? अभियान के रूप में दिल्ली की तीन चौथाई जनता को क्या मिला?

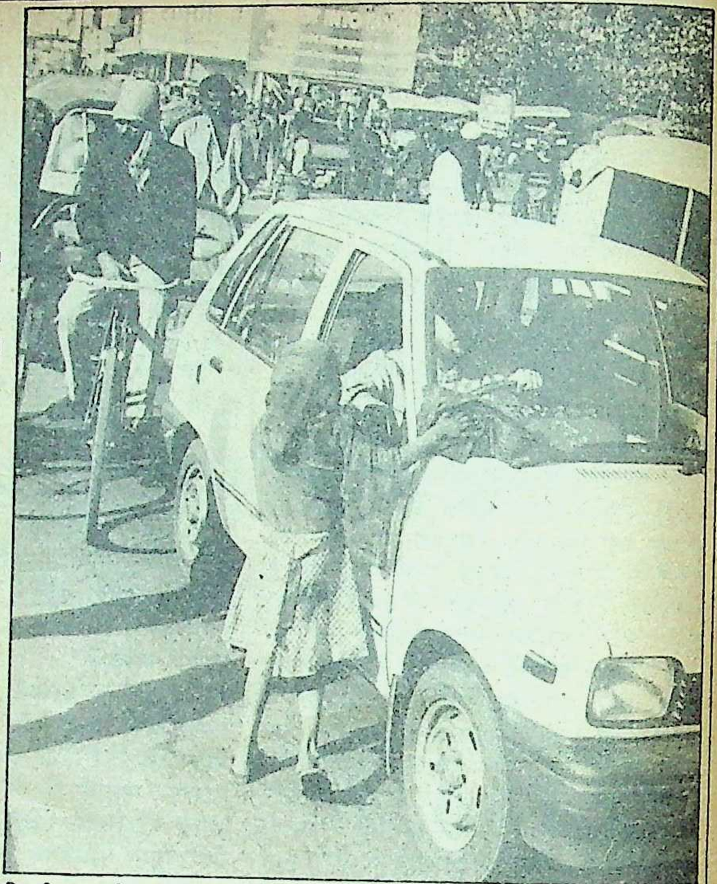

दिल्ली जस की तस

"क्या बात है कि आज सफाई कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी से झाड़ू लगा रहे हैं? कूड़ा-करकट हटाने वाली ट्रक आ चुकी है। सामने सड़क के दोनों ओर लाल गिट्टियां बिछायी जा रही हैं। हमारी कालोनी की यह किस्मत कैसे पलट गयी?"

मदनगिरि (दक्षिण दिल्ली) के रामलाल ने पड़ोसी अशोक से पूछा। जवाब में देर न लगी, "उपराज्यपाल आ रहे हैं न! पर क्या वे हमारी गलियों के इन कीचड़भरे रास्तों में भी आयेंगे? यहां के खुले, बजबजाते नाले, मलमूत्र से भरे, टूटे-फूटे शौचालय और दर्जनों की तादाद में घूमते सुअरों का भी मुआयना करेंगे?"

राजधानी की लगभग तीन-चौथाई आबादी की हालत कमोबेश यही है। गोकि दिल्ली को बेहतर बनाने का एक पखवाड़े का बहुप्रचारित अभियान तीन-चार सप्ताह पहले ही बीत चुका है। कुछ काम हुआ या नहीं, इसकी खबर दिल्लीवासियों को भले न हो, किंतु धुआंधार कागजी प्रचार और जगह-जगह लगे, 'मेरी दिल्ली मेरी शान' जैसे होडिंगों के दर्शन जरूर हुए हैं। एक जानकार सूत्र के अनुसार अखबारी प्रचार पर ही १५ लाख रुपए खर्च किये गये हैं। फिल्में, कैसेट व स्टिकर्स अलग से तैयार हुए, जिन्हें कुछ कंपनियों-जिनमें से एक शराब बनाती है—ने प्रायोजित किया।

उपराज्यपाल रोमेश भंडारी, जिनकी पहल पर अभियान शुरू हुआ था, स्वयं स्वीकारते हैं कि दिल्ली को स्वच्छ-सुंदर बनाने की इस मुहिम से महानगरी में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली प्रशासन के एक उच्चाधिकारी ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहा, "विषम, विकराल समस्याओं से ग्रस्त दिल्ली को १५ दिन तो क्या हम १५ साल में भी बेहतर नहीं बना सकते। कुछ लीपापोती भले ही कर लें।" भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल खुराना ने 'माया' से बातचीत में कहा, "दिल्ली दो हैं। एक राजीव की पांच सितारा संस्कृति वाली दिल्ली, दूसरी आम और गरीब आदमी की दिल्ली। यह अभियान भी 'अपना-उत्सव' की तरह ही झुग्गी-झोंपड़ियों और गंदी बस्तियों में निवास कर रही लगभग तीन चौथाई आबादी से कोसों दूर रहा।"

अभियान में शामिल दिल्ली प्रशासन और संबंधित एजेंसियों—नयी दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम व उसका जल, विद्युत व इंजीनियरिंग विभाग—की एक पखवाड़े (९ से २३ दिसंबर) के सफाई, मरम्मत, निर्माण और रख-रखाव के भारी-भरकम आंकड़ों (देखें बाक्स) की कलई खुदबखुद नयी और पुरानी दिल्ली में बसी हजारों बस्तियों में जाने से खुल जाती है। मसलन निम्न आय वर्ग की बस्ती मंगोलपुरी के नाले का गंदा पानी उस पार्क में बहता है, जहां बच्चे खेलते हैं। पास के हैंडपंप का पानी भी वहीं पहुंचता है। "यहां तीज-त्यौहार पर आने वाले सफाई कर्मचारी नाले की गंदगी मुहाने पर ही छोड़ कर चले जाते हैं," बस्ती के 'बी' ब्लाक की बर्तन मांजकर अपने परिवार का गुजारा करने वाली ४५ वर्षीय विधवा राधिका ने यह टिप्पणी करते हुए बताया, "उन १५ दिनों में तो हमारे यहां कुछ हुआ नहीं। यहां बने ७ पाखानों की सफाई के लिए बस एक जमादार है। पाखानों मे बिजली तक नहीं लगी। रात-बिरात जाते हुए गुंडों का डर बराबर बना रहता है।" ब्रजपुरी, सुलतानपुरी, नागलोई, तिगड़ी, जैतपुर, मोलड़बंद एक्सटेंशन, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी की भी हालत इससे बेहतर नहीं है। सुंदरनगरी, में गत वर्ष हैजा फैलने और अनेक मौतें होने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी सपत्नीक वहां दौरा करने गये थे। इसके बावजूद वहां के निवासियों की शिकायत है कि वहां पेय जल की लाइनें तो बिछ गयीं, किंतु पानी की नियमित आपूर्ति अभी भी नहीं होती।

मध्य आय समूह की कालोनी अशोक विहार फेज-२ में भी मुख्य सड़क से लगे नाले के ठहरे गंदे पानी, कीचड़ और कूड़े-करकट से आसपास के घरों में मच्छरों की भरमार है। निकटवर्ती पाकेट-बी के खुले स्थल पर कूड़े का पहाड़ लगा रहता है। बाजार

सरकारिया कमेटी का
केवल दिल्ली के लिए है

सरकार बहरी है: भाजपा द्वारा मूक प्रदर्शन

दावा दिल्ली प्रशासन का

- बेहतर दिल्ली अभियान के दौरान ३७७६ किमी नालियों, १६६५ किमी सीवर लाइनों, ७४६१ मेनहोलों और १३७७ खुले मेनहोलों की सफाई व रखरखाव किया गया और ६९२८ ट्रक मलबा हटाया गया।
- इंजीनियरिंग विभाग ने २७३४१ वर्ग मीटर सड़क की मरम्मत, २.१२ लाख मीटर सड़क पर मार्किंग, ४२४ जेबरा क्रासिंग, १००४ साइनबोर्डों व ४२२०६ मीटर लंबी ग्रिलों को रंगने और मरम्मत, ९५४ जन सुविधाओं, ८५७० वर्ग मीटर फुटपाथों और १६ पार्कों की मरम्मत की।
- जल प्रदाय संस्थान ने विभिन्न सार्वजनिक नलों पर १४१४ टोटियां लगायीं और ९६४ पानी के नमूनों की जांच की।
- नई दिल्ली नगरपालिका ने अभियान के दौरान ४९९४ टन कूड़ा, २९० ट्रक मलबा हटाया, ६८९४ वर्ग मीटर फुटपाथ, सड़कों की मरम्मत की, ६२ कूड़ेदान, ७२ स्पीडब्रेकर व १८७ मेनहोल ढक्कन लगाये, ४७० पानी के रिसावों की मरम्मत की और ११८ किमी लंबी सीवर लाइन की सफाई की।

के लिए छोड़ी गयी जगह में अनधिकृत झुग्गी-झोंपड़ियां बन गयी हैं। पटेल नगर की मुख्य सड़क के ऐन सामने की श्रमिक बहुल बस्ती रंजीत नगर की भी यही दास्तान है जो मार्च '८७ में अधिसूचना के जरिये दिल्ली नगर निगम के अधीन हुई थी। यहां के चौड़े नाले में मल-मूत्र और कूड़ा-करकट दूर-दूर से बहकर आता है। गलियों की खुली नालियां बजबजाती रहती हैं।

बेहतर दिल्ली अभियान के संबंध में दिल्ली नगर निगम में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस समूची प्रक्रिया से उसे जिस प्रकार अलग-थलग रखा गया, वैसे ही आम दिल्लीवासियों को भी रखा गया है। अधिकांश को तो इसकी खबर तक न थी। होर्डिंग और पोस्टर भी ऐसे प्रमुख व चुनिंदा जगहों पर लगाये गये, जहां के लोगों को पहले से ही अखबारों के जरिये जानकारी थी। नतीजतन कनाट प्लेस जैसे प्रमुख स्थल पर मौजूद इक्का-दुक्का शौचालयों में नयी लिखी इबारत के बावजूद वहां की सड़कों, रास्तो में बहता-फैलता पेशाब बरकरार है।

जब कनाट प्लेस का यह हाल है, तो आम बस्तियों का क्या होगा, यह किसी से छिपा नही है। नारायणा गांव की गृहिणी सुश्री रेनू बाला ने 'माया' से बातचीत में कहा, "यदि बेहतर दिल्ली अभियान में स्थानीय प्रशासन ने हम महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय ही बनवा दिया होता, तो भी उसका मतलब होता।"

—त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

सचाई के आयने में

- लगभग ८० लाख आबादी वाले दिल्ली में साढ़े ७ लाख मकानों की कमी है, जबकि डीडीए मात्र ५ हजार मकान प्रति वर्ष बनाता है।
- ५४ लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ियों, गंदी बस्तियों में रहते हैं।
- लगभग ५ लाख परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।
- रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बढ़कर आज ८ लाख हो गयी है।
- मई १९८८ में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ४४५१ बसें थीं जो नवंबर '८८ में घट कर ४२४० रह गयीं।
- डीटीसी का १९८० का वार्षिक घाटा (१७ करोड़) १९८९ तक २५० करोड़ में बदल गया।
- दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) का १९८० का १३ करोड़ का वार्षिक घाटा, दो बार बिजली दरें बढ़ाने के बावजूद, सालाना २२९ करोड़ पर पहुंच गया है। लगभग १०० करोड़ की बिजली प्रति वर्ष चोरी होती है।

(उपर्युक्त आंकडे मदनलाल खुराना द्वारा 'माया' को प्रदत्त)

महाकुंभ—१९८९

क्या ६ फरवरी सही-सलामत गुजरेगी ?

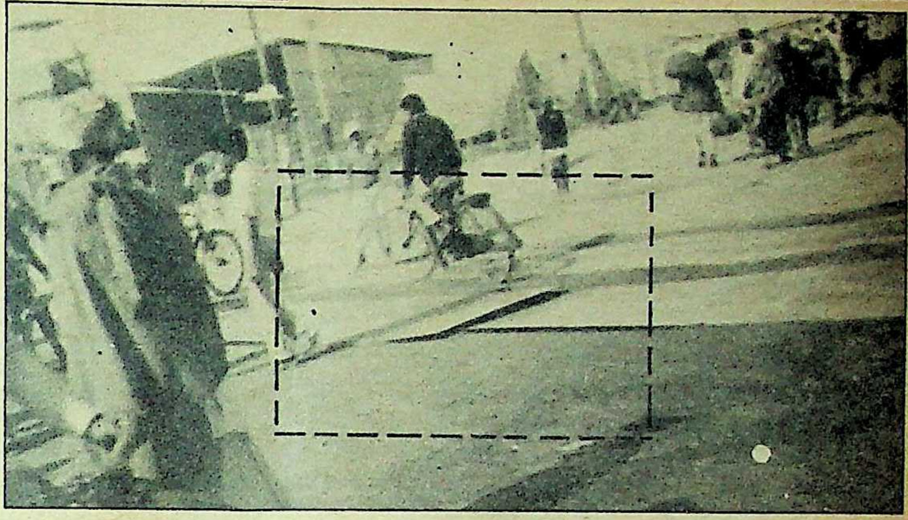

मौत का मुंह:
खुली चैकर प्लेटें

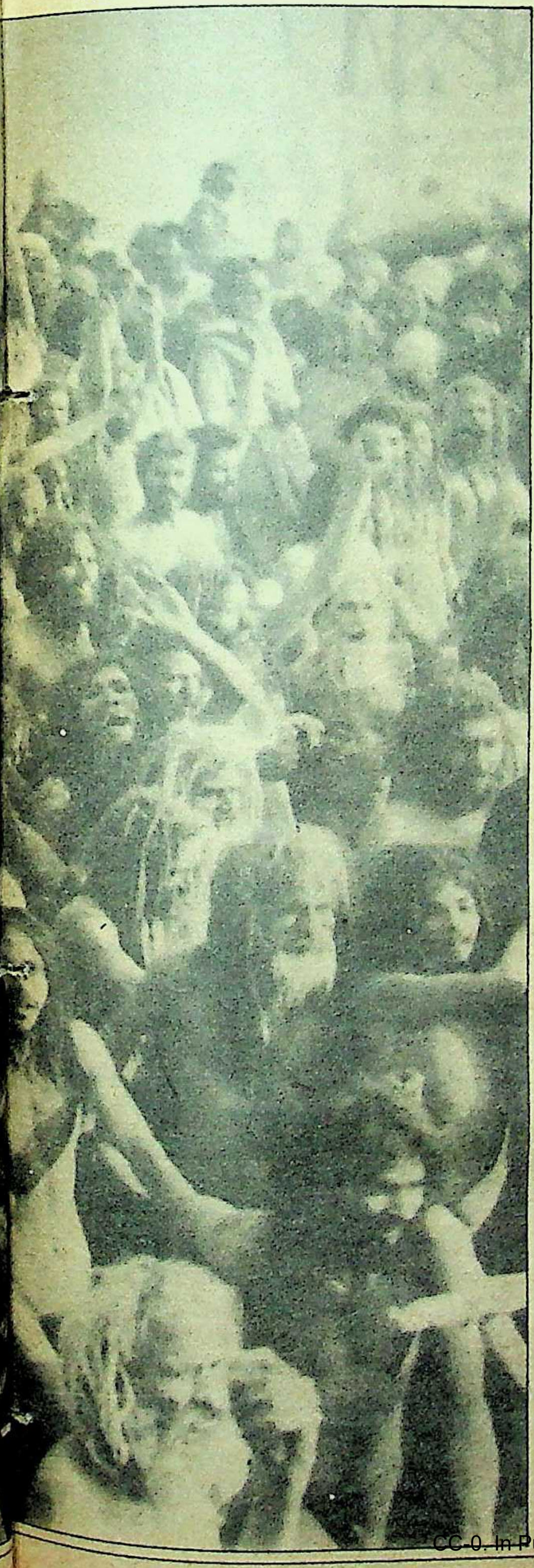

मोक्ष
की तलाश

यद्यपि २० जनवरी को रामकृष्ण मिशन का कुंभ मेला स्थित पंडाल जल कर राख हो गया, लेकिन मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व सही सलामत गुजर गये। इसका मूल कारण यह था कि मेले में अपेक्षित भीड़ नहीं हुई और व्यवस्था को बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यदि प्रमुख पर्व मौनी अमावस्या (६ फरवरी) को एक-डेढ़ करोड़ की अपेक्षित भीड़ मेले में पहुंच गयी, तो क्या निर्विघ्न स्नान की व्यवस्था हो सकेगी? मेले में भगदड़ मचने की बीबीसी की कथित टिप्पणी को एक अफवाह कहा जा सकता है। १९८२ के अर्धकुंभ के समापन पर बाबा भूतनाथ की १९८९ के कुंभ में बड़े हादसे की भविष्यवाणी, मेले में कुव्यवस्था से त्रस्त साधु-संन्यासियों द्वारा प्रशासन कार्यालय के सामने दिये गये हादसा होने के शाप और गंगा नदी के दक्षिणमुखी होकर यमुना में मिलने के अपशकुन को भी अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन क्या मेले में उपस्थित हादसे के दृश्य कारणों को नजरअंदाज करना संभव है? आतंकवादियों की अप्रत्याशित कारगुजारी का डर तो अपनी जगह है ही, साथ ही चैकर प्लेटों के मुंह खुले होने, जर्जरित और जरूरत से ज्यादा सवारी लेकर वैध-अवैध नावों के चलने, बालू से भरी नावों के संगम में आने, संगम पर पर्याप्त सर्चलाइट व्यवस्था के न होने, गहरे पानी से तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए की गयी बल्ली-व्यवस्था के ऐन मौके पर जवाब देने से मौनी अमावस्या के दिन उत्पन्न होनेवाले हादसों से बचने का क्या पुख्ता इंतजाम है? 'माया'-टीम के साथ विनोद मिश्र की रपट:

१४ जनवरी को महाकुंभ का प्रथम महत्वपूर्ण स्नान-मकर संक्रांति—दुर्घटनारहित संपन्न हो गया था। सिर्फ एक नाव डूबी थी, लेकिन पुलिस के मुस्तैद जवानों ने किसी स्नानार्थी को डूबने नहीं दिया। २० जनवरी को 'राम कृष्ण मिशन' का पंडाल जलकर अवश्य राख हो गया। मकर संक्रांति को आधी रात से ही मेला प्रशासक जेएन द्विवेदी और एसएसपी विभूति नारायण राय मोर्चे पर मौजूद थे और वायरलैस से अपने अफसरों को निर्देश दे रहे थे। सारी रात और सारा दिन प्रशासन और पुलिस के अफसर घोड़ों की पीठ पर या पैदल अखाड़ों को स्नान कराने में व्यस्त थे। सूर्यास्त होने पर जब ये अफसर थकान से चूर होकर सोये, तो चैन की नींद सोये मानो पहला युद्ध उन्होंने जीत लिया हो। विजय का यह आह्लाद अगले दिन उनकी बातों में फूट-फूट पड़ता था। वे दावा कर रहे थे कि ४०-५० लाख लोगों ने उस दिन निर्विघ्न स्नान किया था। आयुक्त डीआईजी से लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट तक कह रहे थे कि अब उन्हें भरोसा हो गया है कि वे ६ फरवरी (मौनी अमावस्या) के दिन संगम की ओर बढ़नेवाली डेढ़-दो सौ लाख लोगों की भीड़ को हादसा-रहित स्नान कराकर उनकी निर्विघ्न वापसी को सुनिश्चित करने में कामयाब हो जायेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति का उनका परीक्षण सफल हो गया था।

लेकिन मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या में बड़ा फर्क है। भले ही प्रशासन और पुलिस का दावा हो कि मकर संक्रांति के दिन ४०-५० लाख लोगों ने स्नान किया था, लेकिन जानकार लोगों के अनुसार भीड़ सामान्य माघ मेलों से भी कम थी। इस बार संगम की ओर जाने वाले मार्ग की चौड़ाई डेढ़-दो करोड़ की भीड़ के संचार को ध्यान में रखकर एक हजार फुट रखी गयी थी और संगम की ओर का अधिकांश इलाका सर्कुलेटिंग एरिया के रूप में बिलकुल खाली पड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रशासन मुस्तैद रहता या शिथिल, मकर संक्रांति का स्नान तो हादसारहित होना ही था। मेला प्रशासन इसे अपनी व्यवस्था की सफलता मान रहा था। लेकिन

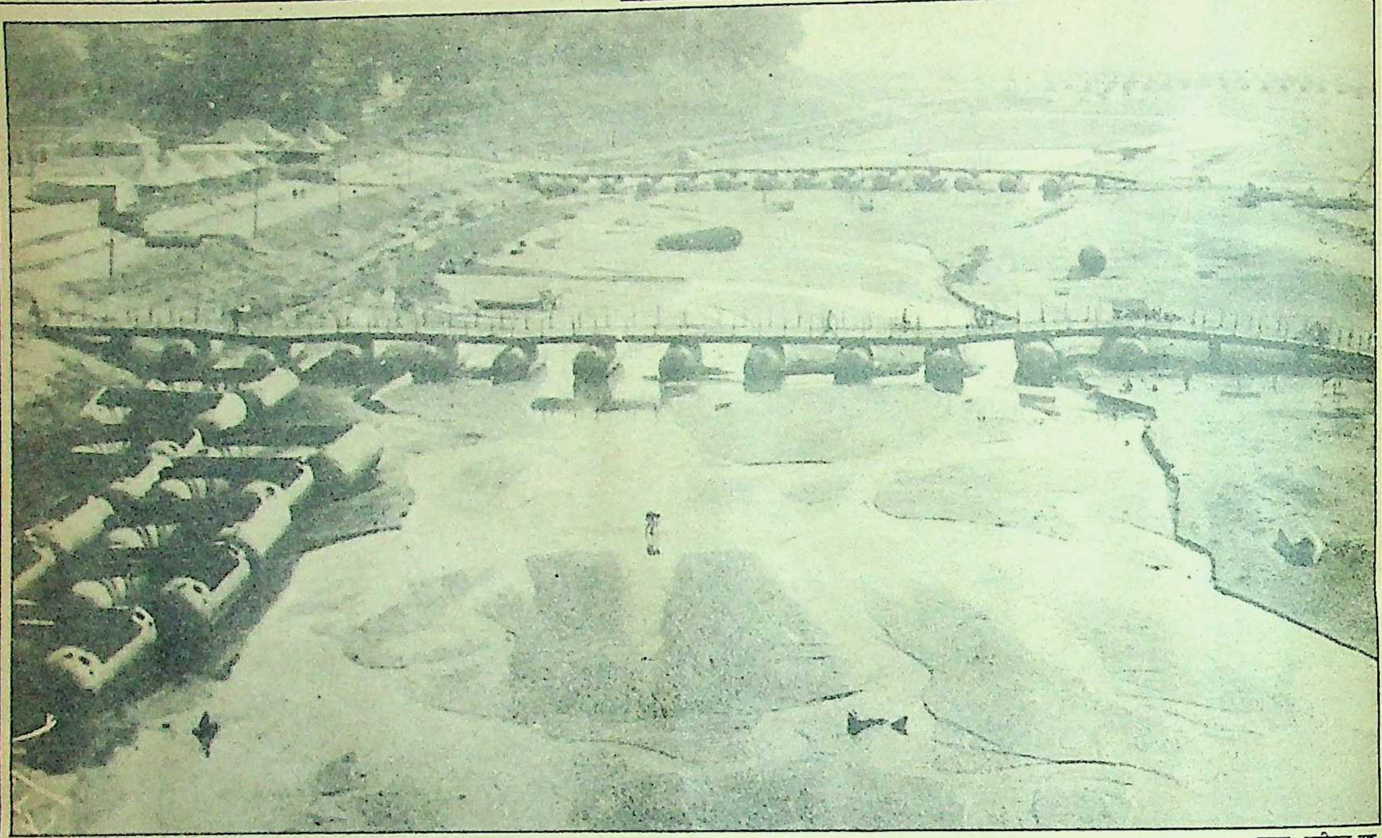

अनुपयोगी पौंटून पुल

छाया : यसीमुल हक

सफलता के उल्लास में उन खामियों की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया, जो गंगा की रेत में छिपी हुई हैं। दरअसल, बांध के नीचे उतरते ही कदम-कदम पर हादसा होने के सारे साजोसामान मौजूद हैं।

लापरवाह अफसर : व्यवस्था की खामियों को मौके पर तैनात अफसर की मुस्तैदी और तत्काल सही और उचित निर्णय लेने की क्षमता बेअसर कर सकती है, लेकिन एक लापरवाह अफसर अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था को चौपट कर सकता है। १९५४ में हुई दुर्घटना का कारण व्यवस्था की खामियां नहीं, बल्कि मौके पर तैनात पुलिस अफसर की लापरवाही थी। उस वक्त गंगा की मुख्य धारा बांध के करीब थी। अखाड़े स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने इन अखाड़ों को देखने वाली भीड़ को रोका जरूर था, लेकिन अखाड़ों के जुलूस की ओर झुकी भीड़ को ढलान पर रोका था, जबकि भीड़ को चढ़ाई की ओर रोकना चाहिए था। बेखबर भीड़ बांध पर चढ़ती चली गयी और ढलान पर जाम भीड़ पर दबाव इतना बढ़ा कि भीड़ पुलिस का घेरा तोड़कर अखाड़ों के जुलूस पर फट पड़ी। वहां हाथी-घोड़े ऊंट चल रहे थे, जो बिदक गये और नागाओं के हाथों में सधे भाले-तलवार भीड़ को निशाना बनाने लगे। इस भीषण हादसे को जिन लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, उनके इसकी स्मृति मात्र से आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मामूली अफसर की लापरवाही ने इतना बड़ा हादसा कर दिया, लेकिन इस बार तो कुछ गजब के अफसर तैनात हैं, जिनकी लापरवाही की कोई मिसाल नहीं। १४ जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान की शुरुआत में ही दो सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने मोर्चे पर मौजूद नहीं थे। इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गयी थी कि वे रात्रि दो बजे ही अखाड़ा क्षेत्र में पहुंच जायेंगे और ५.३० बजे से प्रारंभ होनेवाले अखाड़ों के स्नान का संचालन करेंगे। कंट्रोल टावर पर बैठे मेला प्रशासक और एसएसपी का सारा वायरलैस तंत्र इन मजिस्ट्रेटों को नहीं खोज पाया। अखाड़े स्नान के लिए रवाना होने को खड़े थे और पुलिस अफसर एसएसपी और प्रशासक से बार-बार वायरलैस के जरिए मांग कर रहे थे, "साहब। मजिस्ट्रेट भेजिए, यहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं है और अखाड़ेवाले अब इंतज़ार नहीं कर सकते।" मजबूर होकर मेला प्रशासक को संगम स्नान की व्यवस्था के लिए तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट मिश्र को उनके मोर्चे से हटाकर अखाड़ों के पास भेजा गया। यह लापरवाही कितनी गंभीर थी, इसका अहसास तो युद्ध-क्षेत्र में उस वक्त किया जा सकता है, जब सेनापति किसी अफसर को हमला करने का संकेत भेज रहा हो, लेकिन उसका अफसर मौके पर हाजिर ही न हो।

बेकाबू होने का खतरा : अखाड़े का एक घोड़ा

छाया : मनमोहन शर्मा

संभवत: इस घटना से ही सबक लेकर दो दिन बाद मेला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और यातायात संचालन का काम देख रहे केएन दुबे को विशेष रूप से अखाड़ों के लिए अखाड़ा मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर दिया। उसी दिन दुबे ने अखाड़ों का ऐसा गजब का प्रत्यक्ष जायजा लिया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके द्वारा जायजा लेने के

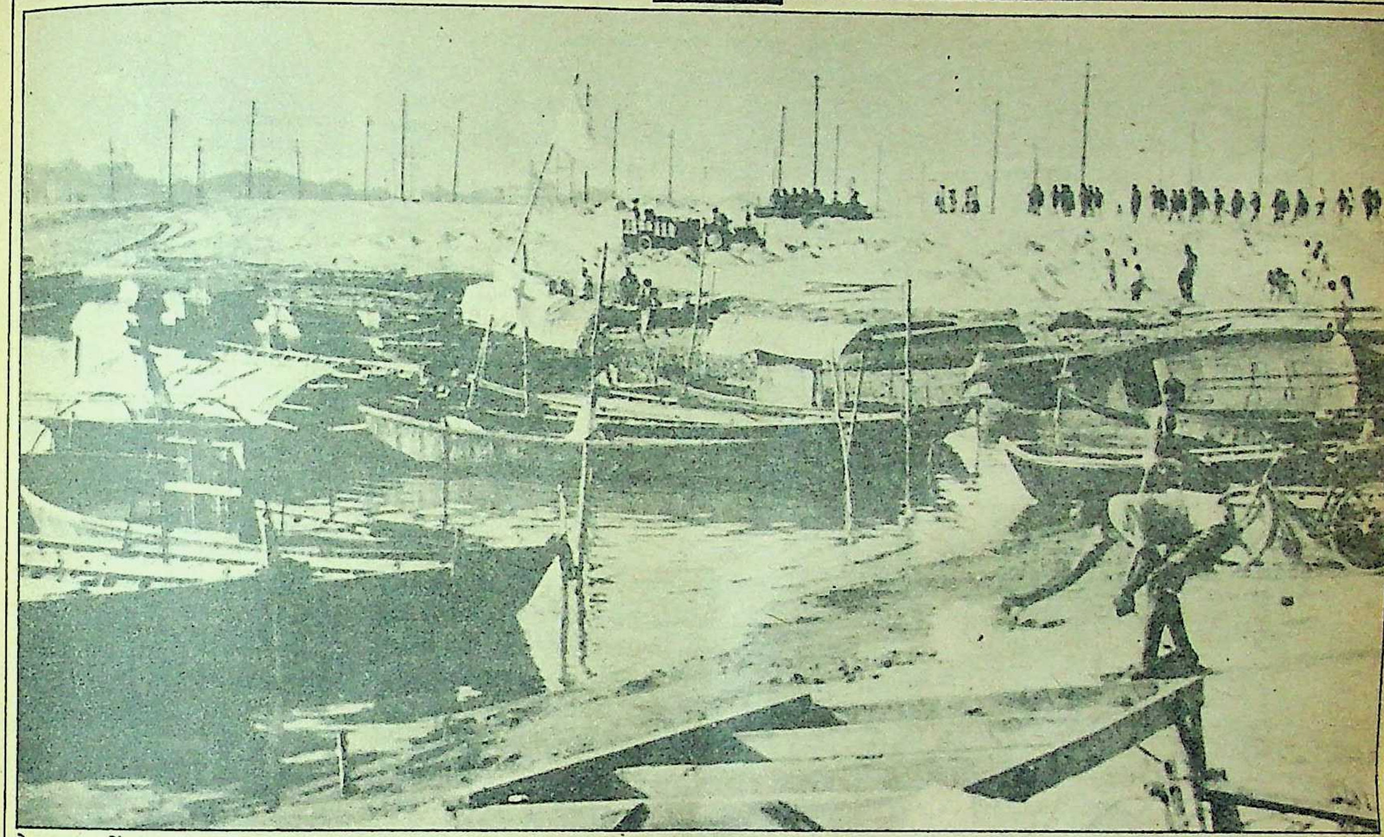

बेलगाम नावें

ठीक एक-डेढ़ घंटे पहले एक नागा ने एक महिला का चिमटे से सिर फोड़ दिया है। वह महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और पुलिस अधिकारी उस मजिस्ट्रेट की तलाश कर रहे थे, जिनसे आदेश प्राप्त करके वे उक्त महिला का मृत्यु पूर्व बयान ले सकते। अखाड़ा मजिस्ट्रेट ने बड़ी मासूमियत से 'माया' से कहा, ''मैं इस घटना के बारे में कैसे जान पाता ? यह घटना तो मेरे वहां जायजा लेने के लिए पहुंचने के पहले हुई थी।'' जिन अखाड़ों का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी दुबे पर है, उनके अखाड़ा-ज्ञान को देखकर ही अपना सिर पीट लेने की इच्छा होने लगती है। ऐसे अफसर सरकारी बंदोबस्त रूपी पेड़ की हर शाख पर मिल जायेंगे जो बिना पूर्व तैयारी के दुनिया के इस सबसे बड़े मेले की व्यवस्था के लिए भेज दिये गये हैं। एक सामान्य अफसर तक यह बात खुलेआम कहता नजर आ जायेगा कि सरकारी अफसर तो ऐश करने के लिए पैदा होता है, वह तो यहां ऐश करने ही आया है, पुण्य कमाने नहीं। कष्ट तो उन लोगों को उठाना ही चाहिए जो धर्म कमाने के लिए यहां आये हैं। क्या ऐसे अफसरों पर हादसारहित कुंभ मेले की जिम्मेदारी सौंप कर निश्चिंत हुआ जा सकता है ? एक बड़े अधिकारी का कहना था, ''हमें तो उन्हीं अधिकारियों से काम चलाना पड़ता है, जो हमें दिये जाते हैं। हम दूसरे प्रदेशों से इनका आयात तो कर नहीं सकते।''

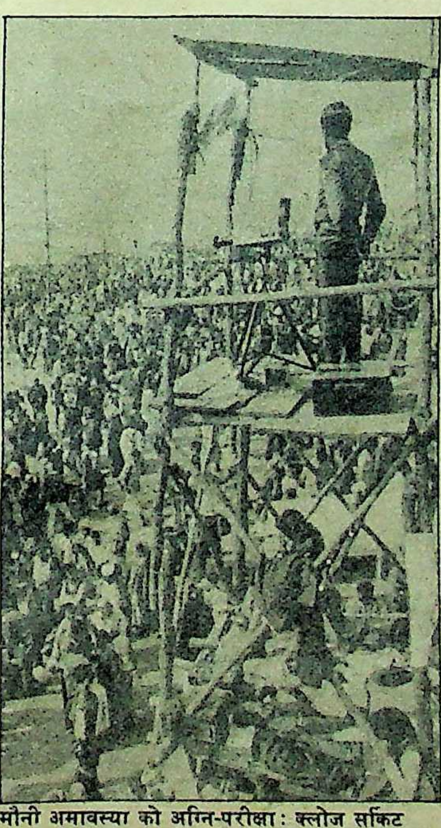

मौनी अमावस्या को अग्नि-परीक्षा : क्लोज सर्किट टीवी की व्यवस्था

छाया : राजेंद्र कुमार

चैकर प्लेट और नट बोल्ट : कलकत्ता के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने दावे के साथ कहा, ''रेत पर गाड़ियां चल सकें, इसके लिए बिछायी गयी वह हर चैकर प्लेट भगदड़ का कारण बन सकती है, जिसके जोड़ खुले हुए हैं। मकर संक्रांति को तो कुछ भी भीड़ नहीं थी। मौनी अमावस्या की भीड़ का रेला नीचे देखकर नहीं चल सकता और इसमें जिस भी व्यक्ति का पैर फंस जायेगा, उसे भीड़ का रेला दबाता हुआ निकल जायेगा और ऐसा एक भी हादसा भगदड़ मचा देने के लिए पर्याप्त है।'' उनका कहना है कि दरअसल इन चैकर प्लेटों को 'ट्रेक वेल्डिंग सिस्टम' (दोनों सिरों पर दो जगह टांके लगाकर) से जोड़ा जाना चाहिए था, जबकि इन्हें क्लब्ज फंसाकर जोड़ा गया है और भारी वाहनों का आवागमन जारी रहने से ये क्लब्ज छिटक कर उखड़ चुके हैं। इसी प्रकार गंगा नदी पर बने पौंटून पुलों पर जड़े साल स्लीपर्स नट-बोल्ट से जोड़े गये हैं और भारी वाहनों के चलने के कारण इनका उखड़ना शुरू हो गया है, जिनकी चैकिंग रोज नहीं हो पा रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ध्यान इस ओर दिलाये जाने पर उनका कहना था कि इन खामियों को पीडब्ल्यूडी से दूर कराने की वे कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। ५० किमी से अधिक मार्गों पर बिछी चैकर प्लेटें अब लाइलाज हैं। उनसे लोग अभी भी घायल हो रहे हैं, यह विडंबना ही है कि हादसारहित स्नान कराने की जिम्मेदारी पुलिस की है और उसने ही संगम तक आने-जाने के मार्गों की व्यूहरचना की है, लेकिन इस व्यूहरचना में बाधा

बननेवाले पीडब्ल्यूडी और जल निगम के कार्यों के लिए वह कोई कठोर कदम नहीं उठा सकती। प्रायः विभागों के परस्पर तालमेल का आलम तो यह है कि नरौरा बांध से गंगा नदी में पानी छोड़ा गया, लेकिन मेला प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं थी। इसका हश्र यह हुआ है कि १२ जनवरी के बाद गंगा नदी का जल स्तर ७५-७६ सेंटीमीटर तक चढ़ गया और कड़कड़ाती ठंड में संगम उत्तरी क्षेत्र के गंगातट के समीप टैंटों में रह रहे कल्पवासियों ने पाया कि वे गंगा की धारा में आ गये हैं और उनके कपड़े, खाने-पीने का सामान आदि गंगा जल में तैरने लगा है। उस क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट ने ऐसे सैकड़ों लोगों को अपने परिसर में प्रश्रय दिया।

महामारी की आशंका : कल्पवासियों के टैंटों में गंगाजल का प्रवेश तक तो गनीमत, लेकिन अब तो सलोरी और मोरी गेट के गंदेनाले का बीमारी फैलाने में सक्षम पानी भी कल्पवासियों के टैंटों में घुसने लगा है। इन गंदे नालों के पानी को जिस पंपिंग सिस्टम से गंगा में जाने से रोका गया है, वह पूरा गंदा पानी पंप नहीं कर पा रहा है, वह बार-बार टूट रहा है। इस गंदे पानी से महामारी फैलने की आशंका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डा० मिश्र लाचार हैं, क्योंकि यह उनके विभाग का मामला नहीं है।

मेला क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय ही नहीं बन पाये हैं। तीन हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने अपने सामने रखा था, लेकिन बमुश्किल दो हजार शौचालय ही बन सके हैं। बहुत से शौचालयों में जल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। अनेक अखाड़ों और मंडलेश्वरों के कैंपों में तो शौचालय हैं ही नहीं। नागा संन्यासियों के शिविर में शौचालय अपर्याप्त होने के कारण गंदगी फैल रही है।

वैसे भी स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही एक-न-एक समस्याओं से घिरा रहा है। डेढ़ मास में ही इस विभाग के अनेक अधिकारी हटाये गये और कर्मचारियों ने हड़ताल की। चर्चा है कि न केवल भरती होनेवाले हर सफाई कर्मचारी से घूस वसूली गयी, बल्कि दवाएं भी कालाबाजार में पहुंचायी गयीं। ९ सेक्टरों में २०-२० बिस्तरों की और सौ बिस्तरों की क्षमता वाला एक बड़ा अस्पताल तो है, लेकिन वहां पर्याप्त दवाएं ही नहीं हैं। स्कूटर से घायल एक व्यक्ति का इलाज सौ बेड के अस्पताल में नहीं हो सका, क्योंकि वहां टिटनेसरोधी इंजेक्शन ही नहीं था, लिहाजा उन्हें शहर के अस्पताल भेजा गया। मकर संक्रांति की थकान से बीमार खुद मेला उपप्रशासक आरपी सिंह को सरकारी अस्पताल से दवा प्राप्त करने में आठ घंटों का समय लगा, क्योंकि वह दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी और उसे बाजार से मंगवाना पड़ा था।

सबसे बड़ा खतरा आतंकवादियों का है। यद्यपि पुलिस और गुप्तचर हर तरह से चाक-चौबंद हैं, लेकिन आतंकवादी अप्रत्याशित हमला करते हैं, इसलिए यह आशंका निर्मूल करना असंभव है।

फिर थल परिवहन की व्यवस्था से किसी

रेत पर गाड़ियां चल सकें, इसके लिए बिछायी गयी वह हर चैकर प्लेट भगदड़ का कारण बन सकती है, जिसके जोड़ खुले हुए हैं। मकर संक्रांति को तो कुछ भी भीड़ नहीं थी। मौनी अमावस्या की भीड़ का रेला नीचे देखकर नहीं चल सकता और इसमें जिस भी व्यक्ति का पैर फंस जायेगा, उसे भीड़ का रेला दबाता हुआ निकल जायेगा और ऐसा एक भी हादसा भगदड़ मचा देने के लिए पर्याप्त है।

साक्षात्कार/विभूति नारायण राय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला

बीबीसी के प्रसारण का कोई महत्व नहीं

कुंभ मेला क्षेत्र में सरकार पुलिस के रूप में ही नजर आती है और कोई भी हादसा होने पर उसकी ही शामत आती है। इस तथ्य से डीआईजी त्रिनाथ मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विभूतिनारायण राय अपरिचित नहीं हैं। ११ हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पिछले ढाई-तीन मास से न केवल कानून-व्यवस्था कायम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें यह भी बतलाया जा रहा है कि कुंभ पर्व क्या है और प्रयाग संगम का माहात्म्य क्या है? पुलिस को जहां तीर्थयात्रियों से शालीन व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं विभिन्न स्कीमों और 'होल्ड अप्स' के जरिए यह पुख्ता व्यवस्था भी की गयी है कि कहीं भीड़ का जमाव न होने पाये और किसी भी प्रकार का हादसा होने की स्थिति में उस क्षेत्र को घेर लिया जाये। पुलिस पूरे संगम क्षेत्र को देखते-देखते खाली भी करा सकती है। यहां प्रस्तुत हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विभूतिनारायण राय से हुई 'माया' की बातचीत के अंश :

माया : *बीबीसी के एक कथित प्रसारण के कारण पूरे देश में यह अफवाह उड़ी हुई है कि ६ फरवरी (मौनी अमावस्या) को हादसा हो सकता है और लाखों लोगों की जान जा सकती है। आपने १४ जनवरी को अपनी व्यवस्था का परीक्षण किया था। इस परीक्षण में व्यवस्था की कौन-सी खामियां आपके ध्यान में आयी हैं?*

राय : *बीबीसी के प्रसारण के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि किसी ने बीबीसी का प्रसारण सुना नहीं। यह बात सिर्फ अफवाह के तौर पर फैली और यदि बीबीसी से ऐसा कोई प्रसारण हुआ भी है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। १४ जनवरी को हम लोगों ने प्रथम परीक्षण किया। व्यवस्था में जो कमियां हम लोगों ने पकड़ीं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। लेकिन जहां ११ हजार पुलिसकर्मी हैं और ४०-५० लाख लोगों को स्नान कराना है, तो कुछ-न-कुछ कमी तो रहेगी ही, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ६ फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पूर्ण रूप से सुरक्षित और निर्विघ्न संपन्न होगा।*

माया : ***चैकर प्लेटों के मुंह या तो जुड़े नहीं या जुड़े हैं, तो गलत तरीके से जुड़े हैं। इन उठे हिस्सों में फंसकर लोग गिर सकते हैं और अफरा-तफरी और भगदड़ मच सकती है।***

राय : *इसके लिए हम सार्वजनिक निर्माण विभागवालों से आग्रह करेंगे कि वे सड़कों का रखरखाव ठीक ढंग से करें।* ■

अब मौनी अमावस्या का इंतजार

छाया: मनमोहन शर्मा

तरह निपट लिए जाने की बात मान भी ली जाये, तो जल परिवहन की अव्यवस्था के कारण संभावी दुर्घटनाओं को रोक पाना शायद प्रशासन के वश से बाहर हो जाये। मेला प्रशासक ने जल परिवहन पर विशेष ध्यान देकर नावों की आवाजाही का मार्ग तो निर्धारित कर दिया है, किंतु किस नाव को लाइसेंस किस कार्य हेतु दिया गया है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। नतीजतन बालू ढोने वाली बड़ी नावें भी यात्रियों को स्नान कराने में लगी हैं। कुछ सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि कभी जिन नावों में शराब बनायी जाती थी, उन्हें भी यात्रियों की सेवा में लगा दिया गया है। यही नहीं, इस बात की भी काफी चर्चा है कि बोट टेस्टर (नाव परीक्षक) ने भारी धनराशि लेकर अनगिनत नावों को लाइसेंस दे दिया है, नतीजतन जर्जर नावें भी यात्रियों की सेवा में लगी हैं, जिनसे किसी समय भी खतरा पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त बालू से लदी हुई बड़ी नावें जिन पर मेले की अवधि में हमेशा प्रतिबंध रहता था (इस बार भी प्रतिबंधित है), वे सरस्वती घाट से संगम की ओर बिना रोक-टोक के आ-जा रही हैं। इन नावों से सबसे बड़ा खतरा छोटी नावों को है, क्योंकि बड़ी नाव से टक्कर होने की स्थिति में छोटी नाव पर सवार यात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इससे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस बार नावों पर कोई सरकारी चिह्न भी अंकित नहीं है जिससे स्नानार्थी गैर-सरकारी कमजोर नावों के खतरे से अपने आपको बचा सकें। इसके अतिरिक्त नदी की कटाई से दस में से छह पौंटून पुलों का बंद कर दिया जाना हादसों को दावत देना है।

यदि ६ फरवरी के आनेवाले अपार जनसमूह के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई, तो कोई बड़ा हादसा हो या न हो, अनेक लोग पीने का पानी न मिलने से ही दम तोड़ सकते हैं।

भ्रष्टाचार और हादसा : जहां भ्रष्टाचार का बोल-बाला हो, वहां कुछ भी घटित हो सकता है। कुंभ मेले में फेरीवालों की बाढ़ आ गयी है। अनेक दुकानदार तो खुले आम कहने लगे हैं कि सरकारी लाइसेंस की फीस के अलावा उन्होंने ऊपर से पैसा खिलाया है। इस बार दुकानों की नीलामी के भाव गत अर्धकुंभ के मुकाबले ८००-९०० प्रतिशत अधिक रहे। यही कारण है कि दुकानदार और फेरीवाले लोगों को जमकर लूट रहे हैं। हर वस्तु के दुगने-तिगुने दाम वसूले जा रहे हैं। वे कैसा सामान बेच रहे हैं, इसकी त्वरित जांच के का साधन मेला प्रशासन के पास नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक खाद्य पदार्थ के ५१ नमूने जांच के लिए दिल्ली भेजे हैं। ७-८ दिनों में भी उनकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी है। सबसे ज्यादा मनमानी तंबू-कनात के ठेकेदार कर रहे हैं। मामूली से सामान के लिए लोग दस-दस दिन उनके यहां चक्कर लगाते हैं, फिर भी सामान नहीं मिलता और जो मनमाना किराया वसूला जा रहा है, वह अलग। प्रशासन को किराया निर्धारित करके सामान मुहैया करने के लिए ठेकेदारों को पाबंद करना चाहिए था। विद्युत विभाग के ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें हर काम के लिए ३५ प्रतिशत कमीशन अफसरों को देना पड़ता है। चर्चा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को कुल काम का १५ प्रतिशत कमीशन

विकास गाइड बुक
1989

इण्टर, हाईस्कूल व जू.हाईस्कूल परीक्षा-1989
सर्वश्रेष्ठ व एकमात्र
परीक्षा पथ प्रदर्शक
विकास
गाइड बुक
सफलता में हर समय
आपके साथ...
आज ही अपने
निकटतम पुस्तक
विक्रेता से खरीदें
→ सम्भावित (Expected) एवं गत वर्षों में पूछे गए दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय व अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर सहित समावेश
→ अनुभवी लेखकों द्वारा सरल भाषा में लिखित
→ आधुनिक तकनीक द्वारा त्रुटि रहित मुद्रण
→ हर विषय पर अलग-अलग उपलब्ध
VAHAN
विकास बुक एजेंसी, आगरा-2

समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं
में सुनिश्चित सफलता
हेतु प्रति माह पढ़ें....
प्रतियोगिता विकास
मासिक
प्रतियोगी ज्ञान-विज्ञान की नवीनतम सूचनाओं का स्वर्णिम साधन

मिलता है, लेकिन २२ प्रतिशत कमीशन इंजीनियर डकार जाते हैं। सिचाई विभाग तो और भी कमाल कर रहा है। दारागंज के उत्तर में गंगा नदी में खड़ा उनका एक यंत्र पिछले डेढ़-दो मास से गंगा की धारा को काट रहा है, लेकिन इसका असर यह हो रहा है कि गंगा के मुख्य स्नान क्षेत्रों के कगार कट रहे हैं और सिचाई विभाग के लोग इन कगारों को ढहने से रोकने के लिए हजारों रुपए की बालू की बोरियां डालकर लाखों वसूल रहे हैं। सिचाई विभाग के अवर अभियता और सहायक अभियंता खुलेआम कहते मिल जायेंगे, "मैंने पैसे देकर यहां अपनी नियुक्ति करायी है, मैं यहां पुण्य कमाने नहीं, पैसा कमाने आया हूं।" एक अन्य अधिकारी का कहना है, यहां आम कल्पवासियों और स्नानार्थियों को छोड़कर कौन है जो पैसा कमाने नहीं आया है। धार्मिक संस्थाएं और अखाड़े, महामंडलेश्वर शंकराचार्यों आदि के पण्डाल क्या दुकानों की तरह नहीं लगते? व्यावसायिक दुकानों की तरह ये भी धार्मिक दुकानें नहीं तो और क्या हैं?"

व्यवस्था की खामियों को मौके पर तैनात अफसर की मुस्तैदी और तत्काल सही और उचित निर्णय लेने की क्षमता बेअसर कर सकती है, लेकिन एक लापरवाह अफसर अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था को चौपट कर सकता है। १९५४ में हुई दुर्घटना का कारण व्यवस्था की खामियां नहीं, बल्कि मौके पर तैनात पुलिस अफसर की लापरवाही थी।

लेकिन इस मेले में कुछ ऐसे वीतरागी सन्यासी भी हैं, जो प्रचार से दूर रात के अंधेरे में गंगा-जमुना की रेत पर विचरण करते हुए मिल जायेंगे। ऐसी ही एक संन्यासी मंडली विचार कर रही थी कि क्या इस कुंभ में कोई हादसा हो सकता है। एक संन्यासी का कहना था, "जब-जब गंगा दक्षिण की ओर झुककर यमुना में मिली हैं, तब-तब कोई-न-कोई दुर्घटना जरूर हुई है। मैं तो अब बांध के उस पार चला जाऊंगा।" जबकि एक अन्य संन्यासी का कहना था, "आप जैसे सिद्धपुरुषों को कुंभ में बने रहना चाहिए, जिससे यहां कोई हादसा न हो।" बहरहाल, सिद्धपुरुषों के रूप में एक दूसरे को संबोधित कर रहे संन्यासी चिंतित हैं, लेकिन तांत्रिक रमेश का कहना है कि उनकी तंत्र विद्या के अनुसार इस बार कुंभ में कोई हादसा नहीं होगा। ऐसा ही विश्वास सरकारी अधिकारी भी दिला रहे हैं, लेकिन यदि चैकर प्लेटों और पौंटूनपुलों के नट-बोल्टों का इतजाम नहीं किया गया, खाद्य पदार्थों की बारीकी से जांच नहीं की गयी, फेरीवालों की भीड़ को कम नहीं किया गया, गंदेनाले गंगा में न मिले, इसका प्रबंध नहीं किया गया, मेला क्षेत्र में पर्याप्त शौचालयों और समुचित सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की गयी और नौकाओं की जांच-पड़ताल नहीं की गयी, तो हादसों की अशंकाएं बनी रहेंगी। १९५४ में हुए हादसे में अनेक लोग तो पानी न मिलने के कारण मौत के मुंह में चले गये थे। इस समय भी पेयजल उपलब्धता की वैसी ही स्थिति है। १४ जनवरी मकर संक्रांति के दिन 'माया' ने पाया कि संगम तट के सर्कुलेटिंग एरिया में कहीं भी नल नहीं था। इस बार पुलिस की भूलभुलैये की व्यवस्था में स्नानार्थियों को काफी पैदल चलना पड़ेगा।

यदि ६ फरवरी के आनेवाले अपार जनसमूह के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई, तो कोई बड़ा हादसा हो या न हो, अनेक लोग पीने का पानी न मिलने से ही दम तोड़ सकते हैं। अलाव की समुचित व्यवस्था न होने के कारण रात की हाड़तोड़ ठंड में अपार गठरियों की तरह पड़े लोगों के 'मोक्ष' प्राप्त कर लेने का अंदेशा अलग से है। ■

यू.पी. हैण्डलूम्स

"महाकुम्भ" के अवसर पर जनता हेतु हथकरघा वस्त्रों की प्रर्दशनी कुम्भ मेला क्षेत्र में विभिन्न आठ स्टालों में उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर (उ०प्र० शासन का संस्थान) के द्वारा लगाई गई है।

कुशल शिल्पियों के द्वारा परम्परागत ढंग से एवं आधुनिकता से सजाये-संवारे हथकरघा वस्त्र, ड्रेस मैटेरियल, शानदार बनारसी साड़ी, आरगेन्जा एवं सूती साड़ियाँ, मुलायम और आरामदेह तौलिये, सूती चादरें, टेपेस्ट्री तथा हथकरघा निगम के द्वारा निर्मित ऊनी वस्त्र/लेडीज/जिण्ट्स शाल ट्वीड, लोई व कम्बल आदि-आदि एक ही स्थल महाकुम्भ मेला के विभिन्न स्टालों व स्थानीय बिक्री केन्द्रों में उपलब्ध हैं।

यू०पी० हैण्डलूम्स के कुम्भ मेला में स्थित समस्त प्रदर्शनी स्टालों व स्थानीय बिक्री केन्द्रों में आपका स्वागत है।

पक्के रंगों, नवीन व अनुपम डिजाइनों में हथकरघा वस्त्र।

HANDLOOMS

उ०प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०
(उ०प्र० शासन का संस्थान)
हथकरघा भवन, जी०टी० रोड, कानपुर।

कलाकार कभी नहीं मरता: प्रसिद्ध रंगकर्मी सफदर हाशमी

सफदर हाशमी हत्याकांड

दमन बनाम स्वतंत्रता

३५ वर्षीय मेधावी रंगकर्मी सफदर हाशमी की निर्मम हत्या ने संपूर्ण स्वतंत्रचेता जनमानस को उद्वेलित किया है। सृजनधर्मियों ने इस जघन्य घटना को अपनी अस्मिता के लिए चुनौती मान कर एकजुट होकर प्रतिरोध का स्वर बुलंद किया है? हाशमी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

"साले कल तक तो हमें देखकर कांपता था। सात दिन की हड़ताल क्या कर ली, हमें आंखें दिखाता है। आज लाल झंडे से हम ही को धमकाता है? भूलो मत। आज तुम इन झुग्गियों में मेरी कृपा से रह रहे हो। अगर मैं चाहूं तो डीडीए के बुलडोजर इस बस्ती को सपाट कर दें।" नाटक 'हल्ला बोल' में उपर्युक्त संवाद बोलने वाले नेता को तो 'सीटू' के कार्यकर्ता नाटक में भगा देते हैं, किंतु विडंबना यह है कि यथार्थ में नाटक करने वालों को धमकाने आया नेता दुबारा आ धमकता है। वह अपने हथियारबंद माफिया गिरोह के साथ नाटक करने वालों और दर्शकों पर पत्थर, डंडे व गोलियां बरसा कर इस कदर हिंसक तांडव करता है कि नाटक के रचयिता व पात्र सफदर हाशमी और एक मजदूर दर्शक राम बहादुर नेपाली की मृत्यु हो जाती है। साहिबाबाद के झंडापुर गांव में पहली जनवरी को जन नाट्य मंच (जनम) और सीटू के तत्वावधान में खेले जा रहे 'हल्ला बोल' नुक्कड़ नाटक

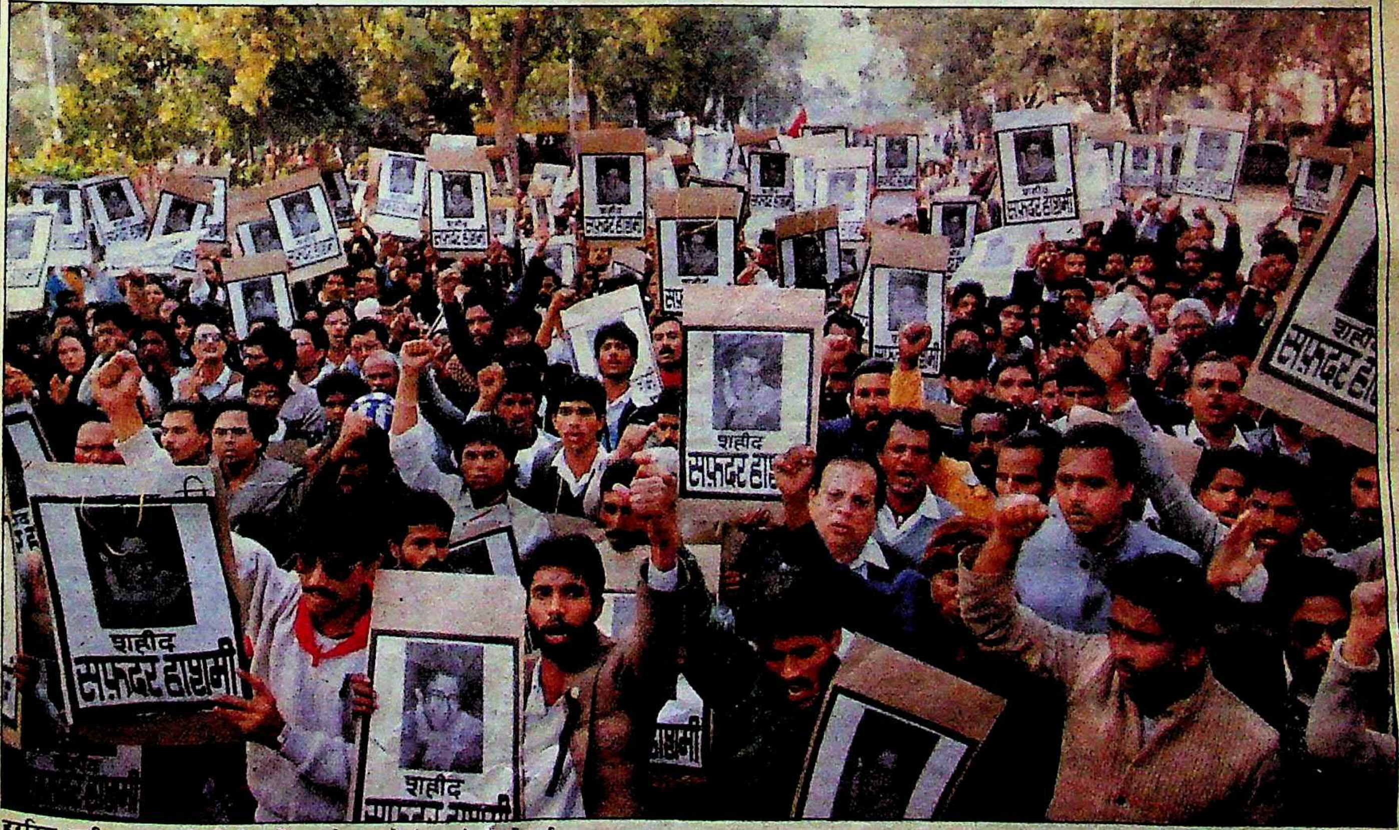

हरदिल अजीज: कांड के विरोध में प्रदर्शन करते 'जनम'- कार्यकर्ता

छाया: सुनील सक्सेना

प्रेम से रचा गया

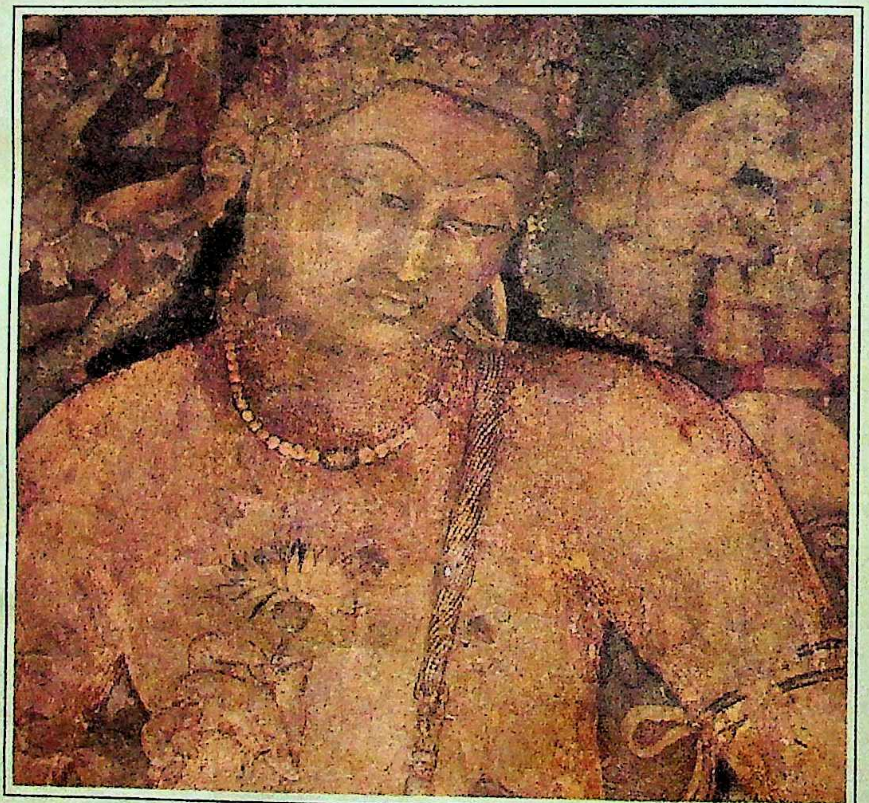

करुणा के अवतार बुद्ध की आंखें कुछ कहती हैं.
इस संसार को प्रेम से निहारती हैं वे.
ज़रा ग़ौर से देखिए.
और याद कीजिए उन कलाकारों को जिन्होंने सदियों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी इन दीवारों पर चित्र रचे.
और हमें सौंप गये बुद्ध के जीवन की छवियां.
मानवता को प्रेरणा देती हुई हमेशा के लिए.

सभ्यता के सीने पर घाव

अ रे रे! नहीं
हमेशा के लिए नहीं.

सिर्फ़ एस.के. साहब और सत्या की जुगल जोड़ी के बने रहने तक.

क्योंकि ऐसे लोग जो अपने जीवन में कोई छाप नहीं छोड़ पाते, समय पर अंकित किसी छाप की कोइ क़ीमत नहीं समझते.

बहरहाल, बुद्ध की आंखों में उदासी गहरा रही है...

यह धरोहर आपकी है इसे बचाइए

यात्रा सिर्फ़ सैर नहीं, एक खोज भी है.

भारत की अनमोल विरासत: समूची दुनिया में बेजोड़.

पर्यटन विभाग भारत सरकार

प्रेमियों ने क्या किया !

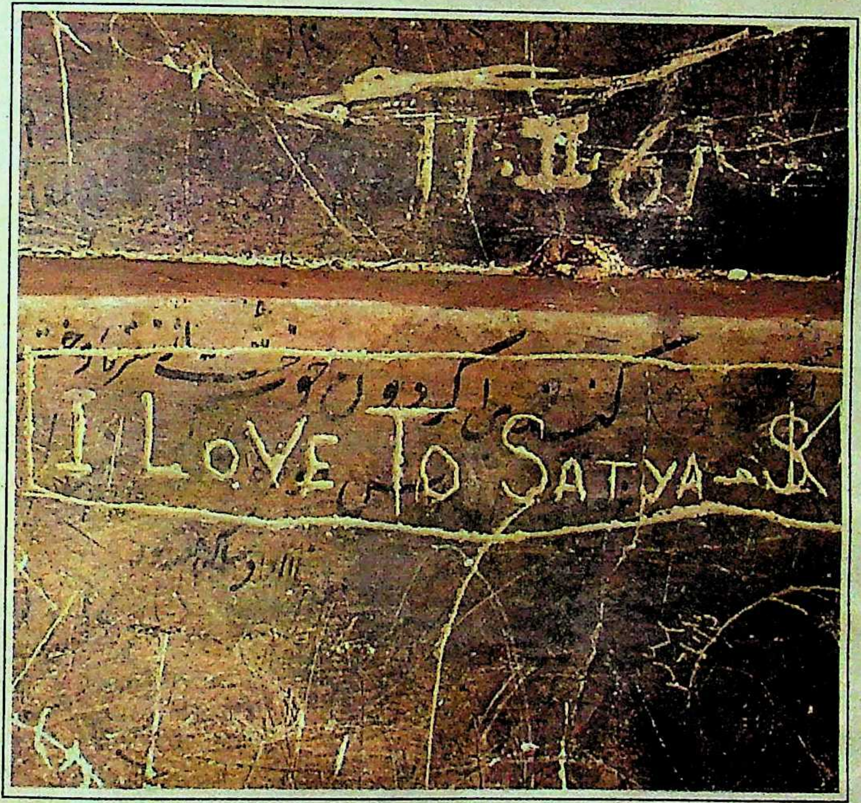

अनगिनत क़िलों, स्मारकों, तीर्थों में गूंजती हुई
5 हज़ार साल की गौरव-गाथा.
और विविधता और वैभव से भरी प्रकृति.
कितने ही रंग और रंगतों में मोहती.
कोई किसी स्मारक को बदशक्ल करता दिखे,
किसी पूजास्थल या तीर्थ का अपमान करे, या
परिवेश को बिगाड़ता गंदा करता नज़र आये तो
आप चुप न बैठिए.
उसे समझाइए.
उसे रोकिए.
उसकी शिकायत कीजिए.
अपनी अनमोल विरासत को बचाइए.
सिर्फ़ यही है आपकी धरोहर.

हम ही रखेंगे
हम ही रखेंगे
अपना भारत सुन्दर

Department of Tourism Government of India

HTA 6238 HIN

के दौरान कांग्रेस समर्थित स्थानीय नगरपालिका चुनावों के उम्मीदवार मुकेश शर्मा और उनके साथियों द्वारा की गयी इस वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नतीजतन समूचे देश में शोक, आक्रोश और प्रतिरोध की जो व्यापक लहर पैदा हुई, वह स्वातंत्र्योत्तर भारत में अभूतपूर्व थी।

सफदर देश की राजधानी के एक अभिन्न अंग थे। यह उनकी गत ३ जनवरी की शवयात्रा—जिसमें लगभग १५ हजार लोग शामिल थे—से उजागर था। उसमें मेहनतकश तबके की महिलाओं से लेकर फैशनेबुल महिलाएं भी थीं जो अपने बच्चों के साथ १२ किलोमीटर लंबे विद्युत शवदाह गृह तक पैदल चलकर गयी थीं। शवदाह गृह में सफदर का शव अग्नि की लपटों की भेंट चढ़ गया। लेकिन सफदर ने मौत से भी बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने व्यापक लोगों को सोचने को मजबूर किया। इसी के चलते लगातार दो दिन (२ और ४ जनवरी को) हजारों लोगों ने गृहमंत्री बूटा सिह की कोठी के सामने जुझारू प्रदर्शन कर सफदर के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की।

अधूरे नाटक को तीसरे दिन (४ जनवरी को) पूरा करने दिल्ली से साहिबाबाद 'जनम' की टोली ही नहीं, सैकड़ों की तादाद में बुद्धिजीवी और कलाकार भी गये थे। झंडापुर में उस दिन 'हल्ला बोल' नाटक को देखने आये हजारों दर्शक दो दिन पूर्व विधवा हुई सूजी आंखों वाली किंतु शांत, गंभीर माला (मलयश्री) हाशमी के सधे, प्रभावपूर्ण अभिनय से अभिभूत हो उठे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और सफदर के अंतरंग सहयोगी डा० अजय तिवारी ने 'माया' को बताया, ''सफदर ने गत माह दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में सीटू द्वारा आयोजित सात दिवसीय हड़ताल के सिलसिले में एक और लोकप्रिय नाटक 'चक्का जाम' लिखा था और उसे राजधानी के अनेक झुग्गी-झोंपड़ी इलाकों में खेला था। उन्हें उस दौरान भी अपने नाटक खेलने के लिए अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ता था। किंतु किसी-न-किसी तरह वे रास्ता निकाल ही लेते थे। गत एक जनवरी को भी जब मुकेश शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस समर्थक लोग झंडापुर गांव (साहिबाबाद) में उस तिराहे पर आये, जहां 'हल्ला बोल' नाटक खेला जा रहा था और यह कहकर धमकाया कि 'हमारे जुलूस को रास्ता देने के लिए नाटक रोक दो' तो सफदर और उनके साथियों ने सोचा कि वे नाटक में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

'जनम' वालों का जहां यह कहना है कि हम साहिबाबाद में यह नाटक मजदूरों को लामबंद करने और उनकी मांगों को बुलंद करने के उद्देश्य से करने गये थे, वहीं स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उनका मकसद स्थानीय नगरपालिका चुनाव में मार्क्सवादी उम्मीदवारों का सीधा प्रचार करना था। घटना-स्थल पर मौजूद अनेक दर्शकों ने बताया कि नाटक के बदस्तूर जारी रहने पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मुकेश शर्मा और बड़ी संख्या में उनके गुंडों ने दुबारा वहां पहुंच कर गोलियों, पत्थरों, लोहे के सरियों और लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया।

सफदर की पत्नी माला जो स्वयं झंडापुर गांव के गत एक जनवरी के मंचन में शामिल थीं, ने 'माया' से बातचीत में कहा, ''कांग्रेसी गुंडों का मकसद एकदम साफ था। वे हत्या करना चाहते थे और उन्होंने यही किया। वे तो हम में से अनेक को मौत के घाट उतारना चाहते थे। किंतु सफदर ने आंख की पुतलियों की तरह हम लोगों की रक्षा करते हुए सारे वार खुद झेले।'' उन्होंने आगे बताया कि हम निहत्थे रंगकर्मियों के दल के सामने लगभग १०० हथियारबंदों की हमलावर टोली थी। इसलिए हमें वहां से डेढ़-दो फर्लांग दूर 'सीटू' कार्यालय में शरण लेनी पड़ी। हमलावरों ने फिर कार्यालय पर हमला किया। सफदर ने हम लोगों को वहां से हटा दिया, पर खुद डटे रहे।

माला ने आगे कहा कि उन्होंने दूसरी महिला कलाकारों के साथ पास के मकान में शरण ली। तब तक हमलावर दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस चुके थे। उन्होंने सफदर के सिर पर लोहे की छड़ों से लगातार वार करना शुरू किया। बाद में वे उन्हें घसीटते हुए बाजार में ले आये। झंडापुर के ही एक दुकानदार ने

दमन से संघर्ष नहीं रुकताः माला हाशमी

छायाः सुनील सक्सेना

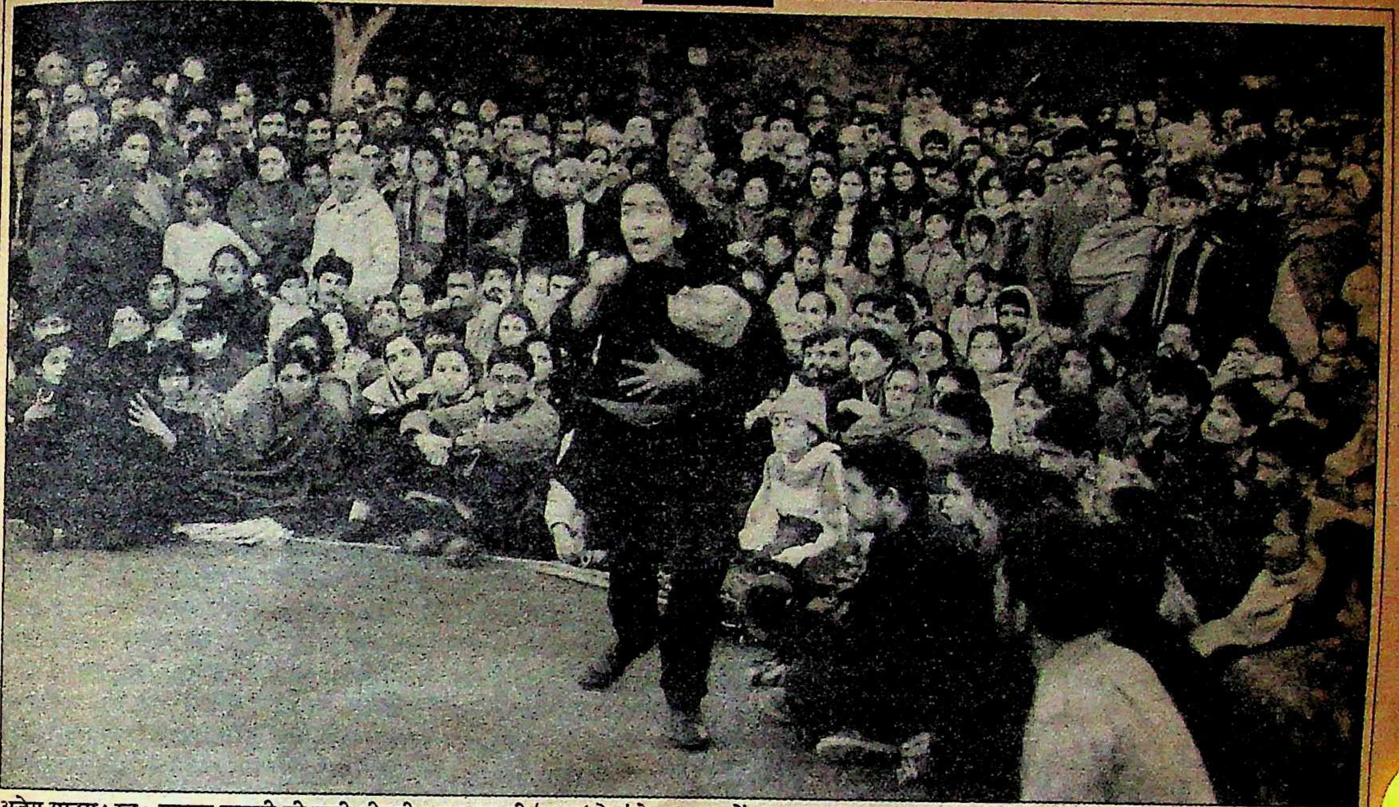

अजेय साहस : स्व० सफदर हाशमी की पत्नी श्रीमती माला हाशमी 'हल्ला बोल' के एक दृश्य में

सफदर हाशमी

एक अपराजेय पौरूष

बहुमुखी प्रतिभा के धनी ३५ वर्षीय सफदर हाशमी एक कुशल अभिनेता, निर्देशक, गायक, वक्ता और फोटोग्राफर थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित ज्वलंत सामाजिक मसलों पर विभिन्न संस्कृतिकर्मियों की एकजुटता में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सफदर की अविचल प्रतिबद्धता, दुर्दम गतिशीलता और अपराजेय संघर्ष ने उन्हें जितना बुद्धिजीवियों के सन्निकट किया, उतना ही सामान्यजनों के भी।

१२ अप्रैल, १९५४ को दिल्ली में जनमे सफदर हाशमी ने १९७५ में दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था। छात्र जीवन से ही भारतीय जन नाट्य मंच (इप्टा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया में सक्रिय रहे। इमरजेंसी पूर्व इप्टा के कांग्रेस मंच से नाटक करने के विरोध में वे उससे अलग हो गये और १९७३ में जन नाट्य मंच (जनम) की स्थापना में अग्रिम भूमिका निभायी। १९७६ में वे मार्क्सवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य बने।

दिल्ली, श्रीनगर और गढ़वाल विश्वविद्यालयों में पढ़ाने और तीन वर्ष तक नयी दिल्ली स्थित पश्चिम बंगाल सूचना केन्द्र में सूचना अधिकारी रहने के बाद एक दिन उन्होंने ऐलान किया, "मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकता।" दिसंबर १९८३ में सफदर पूर्णतया रंग मंच-पार्टी कार्यकर्ता बन गये। तब तक 'जनम' एक व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन में परिवर्तित हो चुका था। उसके जन जीवन पर आधारित नाटक 'मशीन', 'औरत', 'गांव से शहर तक', 'राजा का बाजा', 'हत्यारे' आदि ने न केवल राजधानी, बल्कि देश के विभिन्न भागों में धूम मचा रखी थी। उन्होंने इन नाटकों के लेखन में अहम भूमिका निभाने के अलावा उनके गीत भी लिखे। जन नाट्य मंच अब तक २४ नाटकों की ४ हजार से अधिक प्रस्तुतियां कर चुका है, जिन्हें २५ लाख के लगभग दर्शक देख चुके हैं।

—त्रि०ना०श्री०

अपना नाम न छापने के अनुरोध सहित 'माया' को बताया, "वे (गुंडे) जब उन्हें (सफदर) वहां घसीटते लाये, तो उन्होंने कहा "मुझे छोड़ दो। मैं तो बाहर का हू, नाटक करने आया था।" इस पर एक हमलावर बोला, "साला अभी जिंदा है।" फिर वे उनके सिर को ईंटों से ऐसे कूटने लगे जैसे कोई मसाला कूटता है।"

कांग्रेस ने प्रारंभ में जहां असाधारण रूप से चुप्पी साधी, वहीं रेडियो-दूरदर्शन ने अपनी खबरों में हाशमी को 'मुठभेड़' में घायल बताया। बाद में व्यापक जनाक्रोश से पैंतरा बदल दिया गया। "मुकेश शर्मा और उनके साथी कांग्रेसी नहीं" ऐसा बयान पार्टी महासचिव व गाजियाबाद के सांसद केदारनाथ सिह ने बाद में दिया। उनके इस दावे की काट इसी बात से हो जाती है कि युवक कांग्रेस के साहिबाबाद ब्लाक सचिव करण सिह का नाम सफदर व राम बहादुर के हत्यारों की सूची में है जिसे मार्क्सवादी पार्टी ने नहीं, स्वयं पुलिस ने दर्ज कराया है। "शासक दल, पुलिस और प्रशासन की खुली छूट के बिना दिनदहाड़े व राजधानी से मात्र १५ किलोमीटर दूर ऐसा बर्बर हत्याकांड मुमकिन नहीं था। लोकतंत्र, समाजवाद व अभिव्यक्ति की आज़ादी का दम भरने वाली कांग्रेस का नगरपालिका चुनाव में यह असहिष्णु रवैया है, तो लोकसभा चुनावों में भला क्या होगा?" राजधानी के एक अधिवक्ता राजकिशोर की इस सिलसिले में टिप्पणी थी।

हाशमी की हत्या के खिलाफ गत ९ जनवरी को आयोजित देशव्यापी विरोध दिवस ने तो मानो भौगोलिक सीमाएं ही तोड़ डालीं। दोपहर को दिल्ली विश्वविद्यालय में व ठिठुरती शाम को राजधानी में जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने हजारों दर्शकों के बीच 'हल्ला बोल' नाटक पेश कर रवींद्र भवन तक मौन मशाल जुलूस निकाला गया, वहीं ढाका, बंबई, कराची, काठमांडो, पेरिस, लंदन, मांट्रियल में भी हाशमी की शहादत पर श्रद्धांजलियां अर्पित की गयीं।

हाशमी की हत्या के खिलाफ गत ९ जनवरी को आयोजित देशव्यापी विरोध दिवस ने तो मानो भौगोलिक सीमाएं ही तोड़ डालीं। दोपहर को दिल्ली विश्वविद्यालय में व ठिठुरती शाम को राजधानी में जहा सुप्रीम कोर्ट के सामने हजारों दर्शकों के बीच 'हल्ला बोल' नाटक पेश कर रवीन्द्र भवन तक मौन मशाल जुलूस निकाला गया और बंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़ में विरोध दिवस मनाया गया, वहीं ढाका, कराची, काठमांडो, पेरिस, लंदन, मांट्रियल में भी हाशमी की शहादत पर श्रद्धांजलियां अर्पित की गयीं। राजधानी में ९ जनवरी के विरोध दिवस में प्रख्यात रंगकर्मी ई अल्काजी, एमके रैना, लेखक भीष्म साहनी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष यशपाल, प्रो० जीपी देशपांडे, कथाकार मन्नू भंडारी, न्यायमूर्ति पोत्ती, सोवियत संघ में भारत के पूर्व राजदूत इन्द्र कुमार गुजराल व जोहरा सहगल आदि ने भाग लिया। भीष्म साहनी ने इस हादसे के संबंध में 'माया' से कहा, "गरीबों के बीच रात-दिन काम करने वाले सफदर की आंखों में एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, खुशहाल भारत का नक्शा था। समझौता करना उन्हें गवारा नहीं था। इसीलिए श्रमिक वर्ग, रंगकर्मी, बुद्धिजीवी व राजनीतिक सभी का उन पर भरोसा था। दमन के बावजूद उनका 'जनम' अक्षुण्ण बना है यही उनकी जीत है।"

—त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव

फिल्म समारोह पर हाशमी का साया

अपने जनवादी मिशन के मोरचे पर शहीद हुए रंगकर्मी सफदर हाशमी की हत्या (साहिबाबाद, १ जनवरी) ने किस तरह खासोआम को झकझोर डाला है, इसका एक नायाब नजारा १० जनवरी को नयी दिल्ली में १२वें अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव के शुभारंभ-समारोह में देखा गया। यह नजारा अंतरराष्ट्रीय ख्याति की फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने पेश किया—लोगों का ध्यान इस बात की ओर खींचते हुए कि फिल्मोत्सव से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रतिभावान रंगकर्मियों की हत्यारी, मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना।

जिस वक्त खचाखच भरे सिरी किला प्रेक्षागृह के अंदर सजे-धजे मंच पर अपने-अपने सपने लिये आयोजक और आमंत्रित अतिथि चहलकदमी कर रहे थे, उसी वक्त प्रेक्षागृह के बाहर, गम और गुस्से से भरे कलाकार तथा हाशमी के साथी बैनर लगाकर अपना मौन विरोध प्रकट कर रहे थे। शबाना आजमी सबसे पहले लोगों में छपा हुआ विरोध-पत्र बांटती देखी गयीं। उनके साथ एमएस सथ्यू, एमके रैना तथा रंगमंच के अन्य कलाकार भी थे। पुराने नाट्यकर्मी और विख्यात अभिनेता दिलीप कुमार समेत कई फिल्मी सितारे भी हमदर्दी के साथ, प्रेक्षागृह के बाहर विरोध जता रहे लोगों में शामिल हो गये।

इतने में कार्यक्रम के उद्घोषक कबीर बेदी ने शबाना आजमी को मंच पर आमंत्रित किया—इस अनुरोध के साथ कि वे जिन फिल्मकारों के निर्देशन में काम कर चुकी हैं, उनके बारे में दो शब्द बोलें। मंच पर शबाना के आते ही समूचे प्रेक्षागृह में मौत की सनसनी फैल गयी—मानो हत्यारों का हमला अकेले हाशमी को नहीं, प्रेक्षागृह में एकत्र तमाम लोगों को झेलना पड़ा हो। आयोजन की सारी रंगीनी, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम की सारी चमक-दमक कुछ देर के लिए भूली-बिसरी चीज बन गयी। सब कुछ थम गया। शबाना आजमी ने प्रस्तावित विषय (फिल्म निर्देशकों) पर बोलना 'फिर कभी' के लिए टालकर तत्काल विरोध-पत्र बांचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "पहली जनवरी, '८९ को दिल्ली से सिर्फ १५ किमी दूर साहिबाबाद शहर में एक नाटक खेलते हुए माकपा के सदस्य तथा विख्यात संस्कृतिकर्मी सफदर हाशमी को एक कांग्रेस-समर्थित उम्मीदवार के लोगों ने दिनदहाड़े मार डाला।...हम फिल्म निर्माता और फिल्म प्रेमी ऐसे तंत्र के खिलाफ अपना प्रतिवाद दर्ज करना चाहते हैं जो एक ओर तो सृजनशीलता को बढ़ावा देने का दंभ भरती है, लेकिन दूसरी ओर—ठीक इसके विपरीत—संस्कृतिकर्मियों की हत्या को प्रोत्साहन भी देती है।" इसके बाद, प्रेक्षागृह में शोक और रोष से भरी खामोशी तोड़ते हुए कबीर बेदी ने मंच से आवाज दी, "आपके बीच कोई जनाब कुछ कहना चाहते हैं, तो स्टेज पर तशरीफ ले आयें।" सूचना-प्रसारणमंत्री हरिकिशनलाल भगत ने अपना हाथ ऊपर उठाया और तुरंत मंच पर पहुंचकर, अपनी पार्टी पर हाशमी की हत्या की तोहमत को नकारते हुए जो कुछ कहा, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन इसके साथ ही माहौल का तनाव खतम हो गया, रोशनी फिर धीमी हो गयी और परदे पर व्यावसायिक सिनेमा के नाच-गाने चालू हो गये। **—वरिष्ठ**

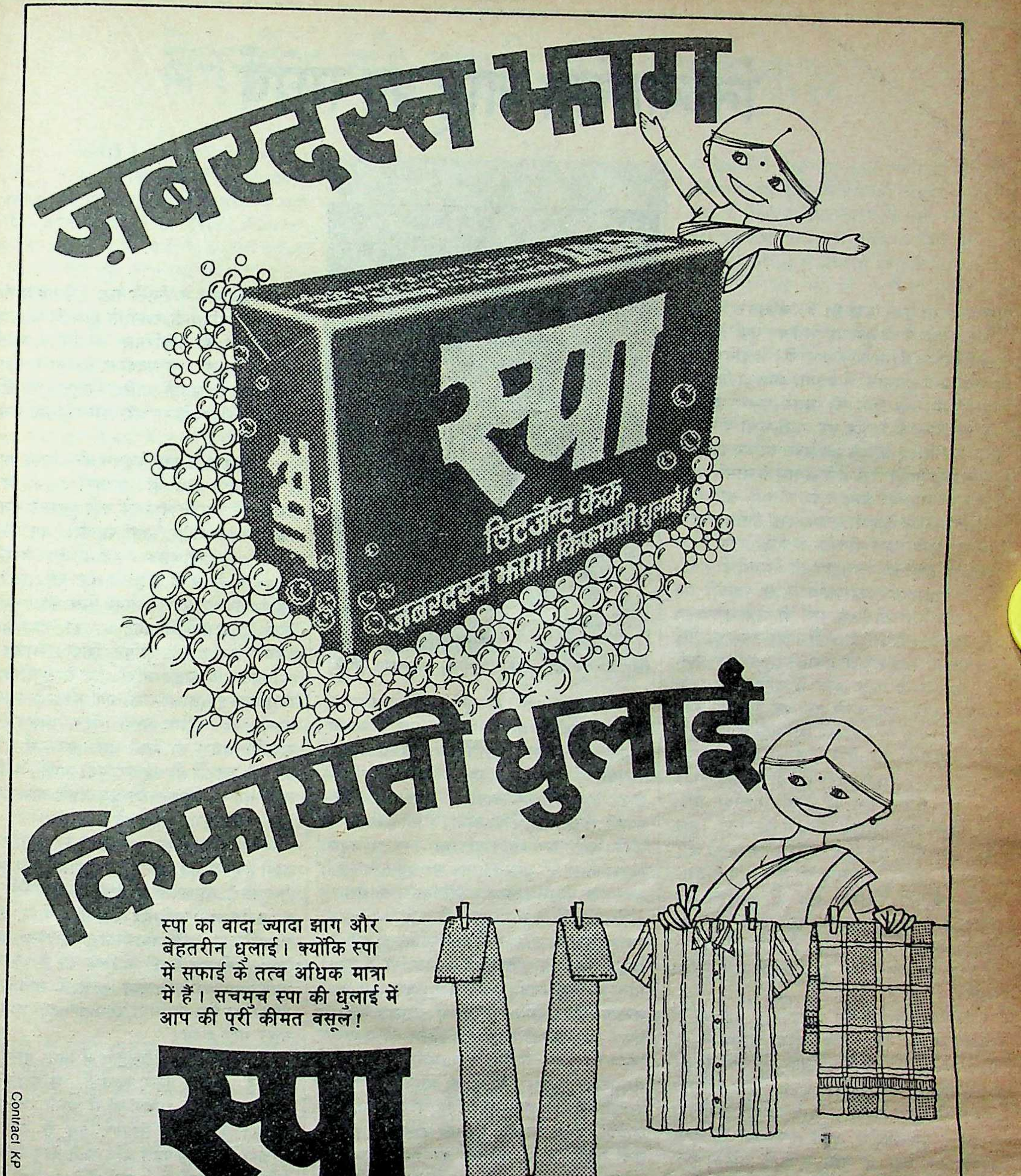
ज़बरदस्त झाग
स्पा
डिटर्जेंट केक
ज़बरदस्त झाग! किफ़ायती धुलाई!
किफ़ायती धुलाई

स्पा का वादा ज्यादा झाग और बेहतरीन धुलाई। क्योंकि स्पा में सफाई के तत्व अधिक मात्रा में हैं। सचमुच स्पा की धुलाई में आप की पूरी कीमत वसूल!

स्पा

डिटर्जेंट केक

A *Kusum* Product

विश्वास के साथ खरीदिये

Contract KP 96-86 HIN

निष्कासित शाह का संघर्ष

एक अरसा गुजर गया है। ३० अक्तूबर, १९६० के अखबारों की सुर्खियां पीली पड़ चुकी हैं। उस दिन तेहरान (ईरान की राजधानी) से दुनिया भर में भेजी गयी सूचनाओं में बताया गया था कि रजा पहलवी के पैदा होने की खबर पाकर हजारों फारसवासी खुशी से झूम उठे, गली-कूचों में नाचने लगे। ८ पौंड ११ औंस के उस बच्चे को जब इस्लामी तरीके और शाही रिवाज से अवाम के सामने लाया गया, तब उसके पास एक मौलवी खड़ा-खड़ा लोहबान जला रहा था, ताकि कोई शैतान पास न फटके। शाही महल की ओर से शाहे-ईरान के इस उत्तराधिकारी को ४१ बंदूकों की सलामी दी गयी।

तख्तताऊस का ख्वाब: रजा पहलवी अब २९ साल के हो गये हैं। वे आज भी, जहां तक संभव है, शाही जिंदगी जीते हैं। लेकिन अब उनके इर्द-गिर्द जुटनेवाली भीड़ पहले के मुकाबले बहुत छोटी होती है। दिसंबर के पहले हफ्ते में यूरोप का अपना अनोखा दौरा शुरू करते हुए जब पहलवी लंदन आये, तब कुछ सौ वफादार ईरानियों ने एक कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था वाले हाल में जाकर उनसे बदस्तूर मुलाकात की। मंच के चारों ओर ईरानी झंडे लगाये गये, दीवारों पर रजा की तस्वीरें सजायी गयीं। काला बुर्का पहने हुई एक औरत ने दुआएं दीं, "शाह लंबी उमर पायें, खूब जीयें,' और उनके चारों ओर खड़े सभी लोगों ने आसमान की ओर हाथ उठाकर उनके स्वर में मिलाये। जैसे ही पहलवी मंच पर पहुंचे, ईरान का राष्ट्रगान पूरे हाल में गूंज उठा। तमाम मेहमानों ने उन पर फूल बरसाये। पहलवी ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले।

निष्कासन के दस साल बाद पहलवी ने तख्तताऊस पर फिर अपना दावा आजमाने का फैसला किया है। उनका इरादा, गुटों में बिखरे ईरानी विपक्ष को एकजुट करना और खोमैनी हुकूमत को खतम करना है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि एक-न-एक दिन वे अपने बाप-दादा की तरह 'महान शाह रजा' के नाम से जाने जायेंगे और शहंशाह तथा खुदा के नुमाइंदे के रूप में माने जायेंगे। उनका कहना था, "आज मैं यहां यह कहने आया हूं कि हमें ईरान को बचाना है, मैं यहां ईरान के अंदर-बाहर की सारी ताकतों को एकजुट करने आया हूं ताकि, खोमैनी हुकूमत के जुल्मोसितम से लड़ा जा सके।"

बिना मुल्क के शाह : रजा (द्वितीय) का बचपन (दायें)

आह्वान की अनसुनी: किंतु अधिकांश पर्यवेक्षक पहलवी की बातों को 'जुनून में बकना' मानते हैं। उनके पास न तो कोई पार्टी है और न कोई राजनीतिक कार्यक्रम। पहलवी का दावा है कि ईरान के अंदर उनके ताकतवर समर्थक हैं, लेकिन ईरानी राजनीति के विश्लेषक बताते हैं कि देश में उनके असर के निशान ढूंढ़े नहीं मिलते। संयुक्त विपक्ष बनाने की उनकी पुकार को अबुलहसन बनी सदर और शापुर बख्तियार जैसे निष्कासन झेल रहे वरिष्ठ नेताओं ने मानो सुना ही न हो। जाहिर है, रजा पहलवी का अभियान बेअसर साबित हो चुका है। दिसंबर के पहले हफ्ते में पश्चिम जर्मनी ने उनकी वीसा की अर्जी नामंजूर कर दी, पहलवी वहां अपने समर्थकों को संबोधित करने की इजाजत नहीं पा सके। उधर ईरानी सरकार ने ब्रिटेन को खबरदार किया कि अगर बीबीसी ने पहलवी के साथ कोई साक्षात्कार प्रसारित किया, तो लंदन और तेहरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली में मुश्किलें आ जायेंगी। इसके बावजूद पहलवी जोर मार रहे हैं। उन्हें यकीन है कि खोमैनी का शासन अंदर से खोखला होता जा रहा है, उसे व्यापक असंतोष का शिकार होना ही है और तब अवाम की चाहत से वे सरकार के मुखिया का प्रतीक बन जायेंगे। वे उस दिन की तैयारी में लग गये हैं। उन्होंने संघर्ष चलाने की कसम ले ली है, चाहे इसके लिए हथियार उठाना भी क्यों न पड़ जाये? एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा, "मैं यह मानता हूं कि हमारी बुनियादी रणनीति मुल्क के अंदर वाली उन ताकतों की जरूरियात पर निर्भर करती है जिनके लिए हम एक मददगार संगठन के तौर पर काम करते हैं। लड़ाई का मैदान तेहरान की गलियां होंगी, लंदन और पेरिस और कैलिफोर्निया के काफी घर नहीं।"

तेहरान से दूर: तेहरान की गलिया पहलवी ने वर्षों पहले देखी थीं। फरवरी १९७९ में जब अवाम की बगावत ने उनके बाप मुहम्मद रजा का तख्ता पलट दिया, तब पहलवी अमरीका में पाइलट (विमान चालक) का प्रशिक्षण ले रहे थे। १९८० में ईरान के शाह की मौत हुई। इसके कई महीने बाद, उधार ली गयी मिस्र की एक शाही कोठी में पहलवी ने अपने आपको 'रजा द्वितीय' (ईरान का शाह) घोषित किया। आजकल वे वाशिंगटन के बाहर चारों ओर से सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं वाली एक कोठी में रहते हैं। उनकी २० वर्षीया पत्नी बेगम यासमां, जहां राजनीतिशास्त्र की डिग्री प्राप्त करने में लगी हैं, पहलवी घर में ही रहकर आने वालों से मिलते और राय-मशविरा करते हुए अपने अभियान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।

निंदा नागवार: अधिकतर ईरानियों के लिए शाही हुकूमत अब अपनी नेकनामी के साथ बेमानी हो चुकी है, तो अपनी बदनामी के साथ बर्बर दमन का प्रतीक बन चुकी है। रजा द्वितीय ने, खुद को पहलवी शासन की बदनामी से दूर रखकर, यह छवि साफ-सुथरी बनाने की कोशिश की है। लेकिन वे अपने बाप की (जिन्होंने मुल्क के संविधान की उपेक्षा कर ईरानवासियों पर कहर ढाया था) निंदा मंजूर नहीं करते।

कुछ भी हो, फिलहाल वे बिना मुल्क के ही शाह हैं। वे जोर देकर कहते हैं, "मैं ईरान वापस जाऊंगा। मौजूदा हालात की मैं उतनी परवाह नहीं करता। जब वक्त आयेगा, तब मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं सबसे पहले और सबसे आगे रहने वाला ईरानी राष्ट्रवादी हूं।" जाहिर है कि रजा पहलवी को अगर कामयाबी हासिल करनी है, तो अपनी कथनी को करनी में बदलना होगा, ईरानी जनता को यकीन दिलाना होगा और यह आसान काम नहीं है।

—वशिष्ठ

बेनजीर की शादी की कशमकश

२६, जुलाई १९८७ का दिन बेशक अहम था, क्योंकि घरवालों और रिश्तेदारों के बेइंतहा इसरार और गुजारिश के बाद मैंने शादी के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया था। हालांकि इससे कब्ल मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे अपनी मां की मर्जी के आगे शादी जैसे निजी काम के लिए भी झुकना पड़ेगा। शादी वह भी मां की लगायी हुई! पूरी तरह से पाकिस्तानी तर्ज पर अमल में लायी गयी शादी! बखुदा मुझे तो खबर भी नहीं थी कि एक दिन मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी करने के लिए राजी होना पड़ेगा जिसको न मैंने कभी करीब से देखा होगा या जिससे कभी मन की बात भी न की होगी। यही नहीं, पाकिस्तान के लोगों को भी इस बात का यकीन नहीं था कि मैं किसी अनजान लड़के से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। आमतौर से लोगों का यही मानना था कि यों ही जिंदगी के सियासी सफर पर बढ़ते हुए मेरी किसी ऐसे से मुलाकात होगी जिसे मैं अपने लायक समझ सकूंगी और उसी से शादी करूंगी। यही वजह थी कि मेरी शादी की खबर पर पाकिस्तान की अवाम कुछ लम्हों के लिए सकते में पड़ गयी थी। जाहिर है, भुट्टो घराने के लोगों की जिंदगी में जिस तरह की तब्दीली आयी थी, उसे देख-जानकर ऐसी शादी की बात सोचना भी मुमकिन नजर नहीं आता था। वैसे भी जिस घराने के लड़के-लड़कियां बैरूने मुल्क (विदेश) तालीम हासिल करने के लिए रह चुके हों, उनके मुताल्लिक आम आदमी का खयाल बदल-सा जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी सियासी जिंदगी, मेरी तालीमो-तरबियत को मद्देनजर रखते हुए लोग तरह-तरह का शक करते थे। अगर कोई मुझे किसी नौजवान से मन लगाकर बात करते देख लेता या किसी से दो चार बार मिलते देख लेता, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता। लेकिन उन अफवाहों में भी लोगों का प्यार होता था, क्योंकि उनका मकसद मुझे बदनाम करना नहीं, बल्कि मेरा घर बसाना होता था।...

मैं शादी के कभी खिलाफ नहीं रही। जब मैं अमरीका तालीम हासिल करने गयी थी, उस वक्त से ही मैंने शादी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में तजरबे हासिल करने शुरू कर दिये थे। मैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों की जिंदगी से सबक हासिल करती थी। देखती थी कि किस तरह से बड़े लोग अपने मिशन पर कायम रहते हुए अजदवाजी (गृहस्थ जीवन) जिंदगी की नांव खेते हैं। मआशरे (समाज) में उनकी जिंदगी का एक अलग रुख होता है और घर में अलग। मआशरे की फलाह (तरक्की) का काम करते हुए अपने पराये का बराबर से खयाल रखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जितना उन्हें समाज की खुशहाली का खयाल होता था, उतना ही अपने बीवी-बच्चों का। ऐसा नहीं था कि उनकी अजदवाजी जिंदगी उनके मआशरी मिशन में आड़े आती। बस फिर क्या था, उन तजरबों ने मुझे ताकत दी। मैंने भी समझ लिया था कि अगर मेरी भी जिंदगी का कोई मिशन बना, तो अजदवाजी जिंदगी आड़े नहीं आयेगी। लेकिन उस वक्त मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं किसी ऐसे से शादी करूंगी जो मेरी ही तरह किसी मिशन की तलाश में होगा और मेरे साथ रहकर मेरी ताकत बन जायेगा। बस इसी धुन में मैं ऐसे आदमी की तलाश में थी, लेकिन मां के इसरार ने मेरी धुन को चकनाचूर कर दिया। हालांकि मुझे आज इस बात का अहसास हो आया है कि अल्लाह जो करता है, बेहतर ही करता है। मुझे इस बात का कतई दुख नहीं है कि मैंने अपने लिए शौहर अपनी मर्जी से क्यों नहीं चुना।

जाती जिंदगी: बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी

जाहिर है, इंसान जितना सोचता है सब कुछ उसे हासिल तो नहीं हो जाता। हां, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी चीज मिल जाती है, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं होता और उसके मिलने से जिस मसर्रत (खुशी) का अहसास होता है उसका बयान नहीं किया जा सकता। अगर यों कहा जाये कि फौजी हुकूमत ने मेरे वालिद का तख्ता पलटकर ही मेरी किस्मत का रुख मोड़ा, तो गलत न होगा। तख्ता पलटे जाने के बाद मार्शल ला नाफिज होने के दौरान मुझसे शादी करने के लिए कई बार कहा गया। लेकिन उस माहौल में शादी के लिए मैं अपने आपको तैयार ही नहीं कर पा रही थी। पापा को जिया की जालिम फौजी हुकूमत ने जेल की सलाखों में जीने के लिए डाल दिया था। पापा पर जो बीत रही थी उसे मैं देख नहीं पा रही थी। ऐसे माहौल में मैं शादी के लिए कैसे राजी होती? फिर अचानक माहौल में ऐसी तब्दीली आयी कि सलाखों के पीछे भी पापा की जिंदगी की सलामती खतरे में पड़ गयी। जिया ने पापा को मार डालने का फैसला कर लिया था। रिश्तेदारों में से कुछ तो उस वक्त भी शादी का पैगाम लेकर आते थे। ऐसा नहीं था कि वे हमारे घराने पर आयी मुसीबत से वाकिफ नहीं थे या उन्हें सदमा नहीं था। उन्हें भी भुट्टो घराने पर आयी आफते-नागहानी पर बड़ा रंज था। शायद इसीलिए बार-बार वे मेरी शादी का इसरार करते, ताकि घर में कोई ऐसा मर्द तो आ जाता, जो उस माहौल में हमारे गम में शरीक हो सकता और हमारी ताकत बनता। लेकिन मैं पापा के साथ किये जा रहे बर्ताव से लड़ने की मन ही मन तैयारी करने में लगी थी। इसीलिए मैंने रिश्तेदारों की बातों को अनसुनी कर दिया था और वे खामोश बैठ गये थे।

कैद की अजीयतें पहुंचाने के बाद जिया ने पापा को फांसी दे दी। पापा के इंतकाल से मेरी जिंदगी में एक अजीब-सा खला पैदा हो गया। मुझे याद है कि कई दिनों तक तो मैं सुध-बुध खोये बैठी थी और घर के लोग मेरी हालत देखकर परेशान हो रहे थे। वैसे भी भुट्टो घराने का यह रिवाज रहा है कि अगर घर में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है, तो कम-से-कम एक साल उस घराने में शादी-ब्याह नहीं होता। इसलिए साल भर तो किसी तरह की शादी-ब्याह की बातचीत नहीं हुई और वक्त गुजरता गया। पापा के इंतकाल ने मुझे फौजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की ताकत दी थी, सो मैं उसी को अपना मिशन मान बैठी। पाकिस्तान को फौजी हुकूमत से छुटकारा दिलाना और जम्हूरियत की बहाली का अलमबरदार बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद रह गया था।...

मुझे याद है कि पापा कहा करते थे, "तुम दोनों (पिंकी और सनम) मुझ पर यकीन करो! मैं तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम दोनों को विदा कर देने के बाद मैं एकदम अकेला हो जाऊंगा और मेरी जिंदगी मेरे लिए बोझ बन जायेगी। लेकिन क्या करूं? मैं मजबूर हूं। शादी-ब्याह भी बहुत जरूरी है। इंसान समाज में रहकर मआशरे के रस्मो-रिवाज से अपने आपको जुदा नहीं रख सकता।" फिर पापा आगे कहते थे, "खैर कोई बात

नहीं शादी कर दूंगा, क्योंकि लड़कियों को हमेशा मां-बाप अपने घर में नहीं बिठा सकते। लेकिन मैं तुम दोनों की ससुराल से वापसी का इंतजार किया करूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिस दिन तुम दोनों अपने ससुराल से वापस आया करोगी मैं तुम लोगों की आंखों में झांककर देखा करूंगा। देखा करूंगा कि इन खूबसूरत आंखों में आंसुओं की खुश्क बूंदे तो नुमाया नहीं हैं। यकीन जानो! अगर मैंने तुम्हारे दुख को जान लिया या मुझे यह पता चल गया कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, तो कसम खुदा कि मैं उसी दिन जाकर तुम्हारे शौहरों को पीटूंगा और हमेशा-हमेशा के लिए तुम लोगों को घर वापस ले आऊंगा।'' पापा इस तरह की बातें सिर्फ मुझे हंसाने के लिए किया करते थे, यकीन दिलाने के लिए कि वे मुझे बहुत चाहते थे। लेकिन आज किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि पापा हमारे बीच रहे ही नहीं कि वे हमारी आंखों में झांककर हमारे दर्द को देखते। इन खयालात के साये में शादी के लिए राजी होना मेरे बस में नहीं था।

पापा के इंतकाल के बाद किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया था। जिया की नजरें मुझ पर और मेरी मां पर आ टिकी थी। जिया हम दोनों को भी मौत के आगोश में सुलाना चाहता था। शायद इसी मकसद के तहत उसने मुझे और मेरी मां को कैद में डाला और अजीयतें पहुंचानी शुरू कर दीं। जाहिर है, जिंदगी के इस मोड़ पर कोई शादी की बात कर भी नहीं सकता था। लेकिन १९८४ में जब मुझे कैद से रिहाई मिली और जिलावतन किया गया, तो इंग्लैंड पहुंचते ही शादी की बातें फिर शुरू हो गयीं। उस वक्त भी मैंने शादी से इंकार कर दिया था। इतने दिनों तक कैद की सलाखों के बीच तनहा रहते-रहते मैं तनहाई पसंद करने लगी थी और मुझे किसी से मिलते हुए कोफ्त होता था। ऐसे में शादी के लिए राजी होना बहुत मुश्किल था। कई बार मैं खुद अपने आपको समझाने की कोशिश करती, लेकिन समझा न पाती। मुझे हर आदमी पर शक होने लगा था। किसी पर मैं ऐतबार नहीं कर पा रही थी। हालत यह थी कि कभी-कभी तो घर के लोग भी मुझे अजनबी लगते थे। ऐसे में किसी अजनबी मर्द के आगोश में जाना मेरे लिए मुश्किल था। शायद उस वक्त मैं अपने शौहर को भी खुश न कर पाती, क्योंकि हर ऐतबार से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। इसलिए एक दिन तंग आकर मैंने मां से कहा था, ''मां तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश क्यों नहीं करतीं? जब मैं कह रही हूं कि फिलहाल मैं शादी नहीं कर सकती, तो बार-बार मुझसे शादी करने का इसरार क्यों करती हो? क्या तुम यही चाहती हो कि मैं शादी करके इस पाक रिश्ते से भी हाथ धो बैठूं?...

जुलाई १९८५ में मेरे घराने के लोग इंग्लैंड आये। मां और मेरी खाला इस बार पाकिस्तान के मशहूर जमींदार घराने के लड़के का रिश्ता लेकर आयी थीं। उनका कहना था कि जरदारी घराने में शादी करने से जिंदगी बन जायेगी, क्योंकि घराने में सभी लोग शरीफ हैं और तालीमयाफ्ता भी। मन्ना खाला तो जैसे तय करके आयी थीं कि इस बार वे किसी भी हालत में मुझे राजी करके ही दम लेंगी। जब भी साथ बैठतीं उनकी जबान पर दो ही नाम होते। जरदारी और आसिफ! अकेले में बैठकर मुझे आसिफ के बारे में बतातीं और जरदारी घराने की शानो-शौकत की तफसील बयान करतीं। उन्होंने मुझसे बताया था कि आसिफ के बारे में फैसला करने से पहले उन्होंने उनके घर वालों से उनके बारे में सभी जानकारियां हासिल कर ली हैं और आसिफ को हर पहलू और हर जाविए से जांच-परख लिया है। एक दिन जब मन्ना खाला अकेले मेरे साथ बैठी थीं, तो बोल पड़ीं, ''बेटी! आसिफ बहुत अच्छा लड़का है। तालीमयाफ्ता भी है। पिटेरो कैडेट कालेज और लंदन सेंटर आफ इकानामिक एण्ड पोलिटिकल स्टडीज में तालीम हासिल की है उसने। पेशे से जमींदार ही समझो। जमीन जायदाद ही इतनी है कि उससे संभाले नहीं संभलती। यही नहीं, मकानात बनवाने का भी उसका बहुत बड़ा कारोबार है। सच पूछो, तो उस घर में किसी चीज की कमी नहीं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तू उस घर जाकर फूलों की सेज पर लेटेगी। फिर शराफत, इज्जत, दौलत ही तो किसी घराने की पहचान बनाती है। क्या नहीं है जरदारी घराने के पास? शराफत का डंका बज रहा है, मआशरे में किसी से कम इज्जत नहीं है और दौलत की भी कमी नहीं। मैं तो कहती हूं कि बस एक बार तू 'हां' कर दे। देखना फिर तेरी मन्ना खाला सच कहती थी या नहीं।''

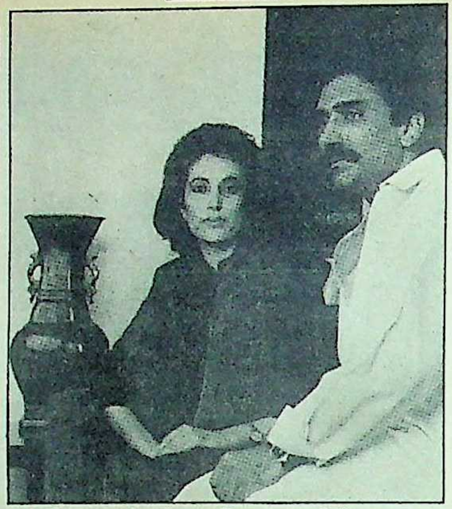

मां की पसंद: बेनजीर आसिफ जरदारी के साथ

बहुत मुमकिन था कि जिस तरह से मन्ना खाला शादी की धुन बांधे हुई थीं, मैं शादी के लिए राजी हो जाती। लेकिन मेरी तकदीर मुझसे चार कदम आगे ही चल रही थी। मन्ना खाला से बातचीत के एक महीने बाद ही मेरे भाई शाहनवाज का खून कर दिया गया। शाहनवाज की मौत से मैं बेहद टूट गयी। एक बार फिर मैंने साल दो साल शादी की बात न करने का फैसला कर लिया।...

मुझे मन्ना खाला पर आज भी फख्र है। मेरे लगातार इनकार करते रहने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरें पाकिस्तान लौटने के सात महीने बाद नवंबर में उन्होंने मेरी रिश्ते की बहन फाखरी के घर आसिफ को दावत पर बुला लिया और मुझे बताया तक नहीं। उन्होंने आसिफ से सूट पहनकर आने के लिए कहा था, ताकि पहली नजर में ही वह मेरी आंखों में जंच जाये और मैं उसे पसंद कर लूं। दावत के दिन मुझे भी फाखरी ने बुलाया। चूंकि मुझे मन्ना खाला की साजिश की पहले से कोई खबर नहीं थी, इसलिए मैं फाखरी के घर पहुंच गयी। घर में अच्छे खासे रिश्तेदार जमा थे। अचानक किसी के मुंह से 'आसिफ' की आवाज आयी। मैंने इधर-उधर घूमकर देखा और पलक झपकते ही मन्ना खाला की साजिश का मुझे अहसास हो गया। खैर! अब तो आ ही गयी थी, सो करती क्या? आसिफ साहब को लाकर मेरे करीब बिठा दिया गया और औरतें मुझसे उनका तार्रुफ (परिचय) कराने में मशगूल हो गयीं। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि पहली मुलाकात में ही हम दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गयी थी। मन्ना खाला ने माहौल का जायजा लेते ही बीच में टपकना बेहतर समझा था, ताकि तकरार रुक जाये। वे बड़ी खामोशी से आयीं और आसिफ को लेकर चली गयीं। आसिफ के जाते ही मुझे राहत मिली, क्योंकि उस दिन सुबह से शाम तक मैं पार्टी के बहस-मुबाहसों से जूझी थी, इसलिए मजीद किसी बहस में उलझना नहीं चाहती थी।

आसिफ के जाने के बाद मैं खयालों की दुनिया में खो गयी। जाहिर है, जिस आदमी का नाम इतने दिनों से सुन रही थी उसको देखने के बाद, उससे बातें करने के बाद अहसास में तब्दीली आना तो लाजिम ही था। तरह-तरह के सवाल जेहन में उभरते और परेशान करते। मैं बार-बार यही सोचती कि क्या आसिफ जैसा शौहर मेरी सियासी जिंदगी से तालमेल बिठा सकेगा? क्योंकि कभी-कभार मुझे रात देर गये भी सियासी मीटिंगों में रहना पड़ेगा। ऐसे में क्या आसिफ मेरी मजबूरी को समझ सकेगा और मेरा साथ देगा? अकसर मुझे घर छोड़कर पाकिस्तान के दूर-दराज इलाकों में घूमने जाना होगा क्या आसिफ मेरा साथ निभा सकेगा? क्या आसिफ इस बात का अहसास कर सकेगा कि जब उसकी बीवी अपनी निजी जरूरतों के लिए वक्त नहीं निकाल पाती, तो उसके लिए वक्त कहां से लायेगी? क्या आसिफ ऐसा शौहर साबित हो सकेगा जो पाकिस्तान की मजलूम अवाम के दर्द को समझ सके और मेरी जिंदगी उनके लिए वक्फ कर सके? बेशक ऐसा करना किसी शौहर के लिए मुमकिन नहीं और इस तरह का बेमिसाल शौहर बनना शायद आसिफ के मुकद्दर में नहीं। इसी तरह सवालात का खुद जवाब देते हुए मैं सोफे पर गुम-सुम बैठी रही। आसिफ का दीदार क्या हो गया, मानो मेरे मन में अर्से से खामोश पड़ी शौहर की चाह ने मुझे बेचैन करने का मौका पा लिया। तभी मुझे पाकिस्तान की अवाम का खयाल सताने लगा। एक

अजीब-सी कशमकश थी। मैं सोच रही थी कि क्या पाकिस्तान की अवाम मेरी शादी से खुश होगी या क्या उसे मेरा जरदारी घराने में शादी करना पसंद आयेगा ? क्योंकि जिया की फौजी हुकूमत ने मुझ पर जितने जुल्म किये थे और जिन्हें मैंने हसते हुए बर्दाश्त किया था, उसे देखकर अवाम मुझे नौजवान फकीर मानने लगी थी। कुछ दोस्तों ने मुझे बताया भी था, "पिंकी ! पाकिस्तान की अवाम ने तो तुम्हें अल्लाह का दोस्त मान लिया है। देखना खयाल रखना उनके अहसास को ठेस नहीं पहुंचे।"...

आसिफ जरदारी ! आसिफ ! आसिफ जरदारी ! मैं यह नाम सुनते-सुनते तंग आ गयी थी। जिधर जांऊं बस इसी शख्स का नाम लिया जाये। मां, खाला और दूसरे रिश्तेदार सभी मुझे राजी करने की कोशिश करते थे। मैंने इनकार कर करके दो साल गुजार दिये, लेकिन जरदारी घराने के लोग खामोश नहीं बैठे। फरवरी १९८७ में मैं टेलीविजन पर अफगानिस्तान से मुताल्लिक बहस में शिरकत के सिलसिले में लंदन पहुंची। आसिफ की सौतेली मां ने भी उसी वक्त लंदन जाने का फैसला किया और लंदन पहुंच गयीं। असल में आसिफ की सौतेली मां और मेरी बहजात खाला बचपन में स्कूल में साथ पढ़ा करती थीं। आसिफ की मां बहजात खाला से मिलने लंदन पहुंची थीं। उन्होंने खाला से मिलकर आसिफ और मेरे रिश्ते की बात की। बस फिर क्या था। खाला भी उसी मुहिम में शरीक हो गयीं और आसिफ के जमाल और हुस्न-एखलाक के गीत गाने लगीं। अब तो मैं और परेशान हो गयी, क्योंकि आसिफ के लिए मेरे सभी रिश्तेदार मुत्तफिक होते जा रहे थे।...

जब मैं कराची वापस पहुंची, तो मज़बूर होकर मुझे आसिफ की मां से मिलना ही पड़ा। उनकी मां मुझसे बोलीं, "बेटी मैं अपने पर फख्र महसूस करूंगी अगर तुम आसिफ के साथ शादी करने को राजी हो जाओगी।" जाहिर है, जो मां अपने बेटे के लिए मुझसे सिफारिश कर रही थी उसे अपने बेटे पर पूरा एतमाद (भरोसा) रहा होगा। लेकिन मां के लिए तो बेटा-बेटा ही होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मैं बोली, "आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हैं। मैं सियासी जिंदगी से वक्त नहीं निकाल पाऊंगी, तो आपका बेटा कैसे खुश रहेगा ?" इस पर आसिफ की मां तपाक से बोल पड़ीं, "नहीं बेटी ऐसा नहीं है। आसिफ तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। वह तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा।" मैं बोली, "पाकिस्तान की अवाम के लिए न जाने मुझे कहां से कहां जाना पड़े ? कितना सफर करना पड़े ? आखिर आसिफ मेरा कितना साथ देगा ?" इस पर भी आसिफ की मां ने मुझे यकीन दिलाया कि उनका बेटा अपने वायदों से पीछे नहीं हटेगा। आसिफ के बारे में इतना जानकर मुझे थोड़ा भरोसा हो गया और मैंने आसिफ से मिलने के लिए पहली बार अपनी रजामंदी सुना दी और आसिफ से मुलाकात करने के लिए लंदन जाने की तैयारी शुरू कर दी।...

मैं आसिफ से मुलाकात करने की गरज से लंदन पहुंच गयी। २२ जुलाई, १९८७ को दिन भर तो मैं सियासी मीटिंगों में ही मसरूफ (व्यस्त) रही। शाम को जब खाली हुई, तो आसिफ से मुलाकात का खयाल फिर आ गया, खैर ! तैयार होकर तारिक (रिश्तेदार) के मकान पर पहुच गयी, जहां मेरी आसिफ से मुलाकात होनी थी। मन्ना खाला सोफे पर बैठी आस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखती हुई काफी पी रही थीं कि तभी घंटी बजी। मैं समझ गयी कि आसिफ आ गये। जिस आराम-कुरसी पर मैं बैठी थी, मैं उस पर और आराम से बैठ गयी, ताकि आसिफ मुझे देखकर वैसा अहसास न करें जैसा आमतौर से जब लड़कियों को पहली बार लड़के देखते हैं, तो होता है।

आसिफ अपनी मां के साथ कमरे में दाखिल हुए। मैंने तिरछी निगाह उन पर डाली। हालांकि इससे कब्ल भी मैं उनसे मिल चुकी थी, लेकिन आज वह मुझे कुछ ज्यादा पसंद आये थे। आसिफ और उनकी मां आदाब-एकराम के बाद सामने सोफे पर बैठ गये। बातचीत शुरू हो गयी। हालांकि सब यहां शादी की बात करने के मकसद से इकट्ठा हुए थे लेकिन कोई शादी की बात छेड़ नहीं रहा था। उस शाम आसिफ की मुझसे बातचीत नहीं हुई। आसिफ चूंकि चश्मा लगाये हुए थे, इसलिए मैं उनकी आंखों के अहसास भी नहीं पढ़ सकी। दूसरी दिन आसिफ ने दर्जन भर गुलाब के फूल बतौर तोहफा भेजे। साथ में उन्होंने मेरी पसंदीदा मिठाई और फल भी भेजे जिसमें आम भी शामिल थे।

हर रोज सुबह मेरी मां, मन्ना खाला और बहजात खाला मुझसे बस एक ही सवाल पूछतीं, "बोलो बेटी ! बताओ तुमने क्या फैसला किया ? क्या आसिफ तुम्हें पसंद हैं ?" मैं सिर्फ इतना कहती, "मां। अभी मैं फैसला नहीं कर पायी।" मुझे न जाने क्या हो गया था ? जितनी बार मैं आसिफ को देख रही थी उनकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। एक बार मन कहता कि 'हां' कर दूं। फिर सोचती की पता नहीं आसिफ अच्छे शौहर साबित होंगे की नहीं ? किसी के चेहरे को या वक्ती एखलाक से उसके ढंके-छिपे तौर-तरीकों का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। फिर सोचती कि जब वालदैन की ख्वाहिश से ही शादी करनी है, तो अजनबी से तो करनी ही होगी, फिर आसिफ के बारे में तो सभी मुत्तफिक हैं कि वे एक अच्छे शौहर साबित होंगे। तभी मुझे अपने मशरिकी (पश्चिमी) दोस्तों का खयाल आता कि न जाने अजनबी से शादी करने पर वे मेरे बारे में क्या सोचें ? क्योंकि मशरिकी तहजीब में तो जाने-समझे लड़के-लड़कियों के बीच ही शादियां होती हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे बारे में गलत राय कायम कर लें कि मैं काफी पिछड़ी हुई हूं। क्योंकि वे मेरी मआशरी मजबूरियां और मजहबी फराएज तो समझ नहीं सकेंगे।

मगर जो किस्मत में लिखा होता है, उसे टाल कौन सकता है? मुकद्दर एक शहद की मक्खी की शक्ल में मेरे इर्द-गिर्द घूम रहा था।

कभी-कभी दिल को दहला देने वाले खयालात भी परेशान करते कि अगर मैंने आसिफ से शादी की और वे मुझे खुश न रख सके या मैं उन्हें खुश न रख सकी और तलाक की नौबत आयी, तो कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा ? कहीं ऐसा न हो कि अभी तो आसिफ अच्छी तरह पेश आ रहे हैं और बाद में मेरी सियासी जिंदगी को बर्दाश्त न कर सकें और तलाक दे दें। ऐसी हालत में भुट्टो घराने का नाम मिट्टी में मिल जायेगा। यंही कशमकश थी जो मुझे किसी फैसले पर नहीं पहुंचने दे रही थी।...

लेकिन आसिफ ने भी पीछा छोड़ा नहीं। वे मुझसें किसी न किसी बहाने मिलने के लिए करीब-करीब हर रोज़ घर आते और तोहफे दे जाते। मैंने भी मौका गनीमत समझा और अनजाने में आसिफ की मुलाकात आक्सफोर्ड के अपने दोस्तों से करायी और उनसे आसिफ के बारे में राय ली। मेरे दोस्तों और मेरी सहेलियों ने भी आसिफ को पसंद किया और मुझसे शादी करने की बात कही। आसिफ के बारे में आम राय अच्छीं देखकर मुझे आसिफ पर भरोसा हो गया और मैंने तारिक से बातचीत आगे बढ़ाने की गुजारिश की। तारिक मेरे कहने पर आसिफ से मिला और बोला, "भाई आसिफ देखो बात बड़ी साफ-सी है। अगर बेनजीर तुमसे शादी कर लेती है, तो तुम्हारा नाम पूरी दुनिया जान जायेगी। ऐसी हालत में तुम्हारी छोटी-सी-छोटी बेजा हरकतों का बेनजीर की शख्सियत पर असर पड़ेगा।" आसिफ ने तारिक की बात समझ ली और ऐसा जवाब दिया कि तारिक भी आसिफ का शिकार हो गया और घर वापस आकर लगा आसिफ के नगमें गाने। उसने कहा, "आसिफ तुम्हें बहुत चाहता है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी।" लेकिन मैंने तारिक की बातों पर यकीन नहीं किया।

मगर जो किस्मत में लिखा होता है, उसे टाल कौन सकता है ? मुकद्दर एक शहद की मक्खी की शक्ल में मेरे इर्द-गिर्द घूम रहा था। आसिफ जब चौथी बार मेरे घर आये थे, तो मैं फतही के साथ विंडसर पार्क घूमने चली गयी थी और आसिफ पोलो मैच देखने गये थे। पार्क में एक शहद की मक्खी ने मेरे हाथ पर डंक मार दिया। रात होते-होते मेरा हाथ बुरी तरह फूल गया। तकलीफ से मैं बेचैन हुई जा रही थी। तभी आसिफ घर आये। मेरे हाथ की सूजन और मेरी तकलीफ देखकर वे परेशान हो गये।

स्पुतनिक
(अंतर्राष्ट्रीय मासिक)

संसार की अनेक
भाषाओं के
साथ-साथ अब
हिंदी में भी

स्पुतनिक
स्पुतनिक
स्पुतनिक

सोवियत नीति, संस्कृति-शिक्षा, विज्ञान, राष्ट्रीय गतिविधि और जनजीवन के विषय में विचारोत्तेजक, रोचक और ज्ञानवर्द्धक सामग्री एवं अपने मित्र-देश की अंतरंग झांकी

वार्षिक चन्दा 55 रुपये
तीन वर्ष का चन्दा 110 रुपये

उपहार में एक बड़ा रंगबिरंगा कैलेंडर केवल तीन वर्ष के ग्राहकों के लिए

स्पुतनिक की प्रति आप अख़बार के हॉकर से मंगा सकते हैं अथवा स्टॉल से ख़रीद सकते हैं।

एक प्रति का मूल्य 5 रुपये

अतिरिक्त सूचना के लिए सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी से संपर्क स्थापित करें 4 ई/4, झंडेवालान एक्सटेंशन
नयी दिल्ली- 110 055

"स्पुतनिक" के लिए डी डी/एम ओ प्रेषित है
तीन वर्ष का चन्दा 110 रुपये
एक वर्ष का चन्दा 55 रुपये
(अवांछनीय काट दीजिये)

मेरा नाम ____________________

पता ____________________

____

यह विज्ञापन और रकम निम्न पते पर भेजिए

नवचेतन बुक्स (प्रा.) लि.
५-ई रानी झांसी रोड
नई दिल्ली-११००५५

राजस्थान पीपल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लि.
चमेलीवाला मार्किट,
एम.आई.रोड, जयपुर-३०२००१

मैगजीन सेन्टर
एम.सी.डी. बिल्डिंग
नं. २, दूसरी मंजिल
देशबन्धु गुप्ता रोड, पहाड़गंज
नई दिल्ली-११००५५

उनके चेहरे से बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आज मुझे अहसास हुआ था कि सचमुच आसिफ मेरे शौहर बनने लायक हैं। उनके चेहरे का उतार-चढ़ाव उनके दिल में मौजूद मेरी मोहब्बत का ऐलान कर रहा था। वे कभी मेरे हाथ की सूजन देखते, कभी दरवाजे की तरफ लपकते। फिर लौटते और सूजन देखकर खामोश खड़े हो जाते। ऐसा लग रहा था कि चाहते हुए भी वे मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। मैं भी एकटक उनके चेहरे को देख रही थी शायद इसलिए कि आज वह वक्त आ गया था जब मुझे अपनी जिंदगी का अहम फैसला करना था। मेरी नजरें उनकी आंखों पर जा टिकी थीं जिनकी सियाही में मेरे हाथ की तकलीफ साफ नुमाया थी। तभी उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, "चलिए मेरे साथ अस्पताल चलिए मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है।" उनके इस जुमले ने मेरे जजबात में तूफान पैदा कर दिया। जजबात ऐसे जजबात ! जिनकी तह में मेरा दर्द खो गया था। फिर भी मैंने अपने पर काबू किया और इनकार के लहजे में सिर हिला दिया, लेकिन वे माने नहीं। दरवाजे पर पलक झपकते ही कार आ गयी। देखते ही देखते डाक्टर मेरे सामने मौजूद हो गये और नजरों से ओझल होने की देर थी कि हाथों में दवाएं लिए आसिफ मेरे सामने एक अजनबी सी उम्मीद के साथ खड़े थे। उसी रात आसिफ हम सबको होटल में खाना खिलाने ले गये। मैं, मां और सनम आसिफ की कार में थीं। साथ में कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी थे। पाकिस्तानी होटल की तलाश में कार सड़कों पर दौड़ती रही और हम रास्ता भूल गये। इस सफर में आसिफ ने मुझे बहुत हंसाया और इस बात का अहसास करा दिया कि वे हर खूबी के मालिक हैं।

आज मुझे अहसास हुआ था कि सचमुच आसिफ मेरे शौहर बनने लायक हैं। उनके चेहरे का उतार-चढ़ाव उनके दिल में मौजूद मेरी मोहब्बत का ऐलान कर रहा था। वे कभी मेरे हाथ की सूजन देखते, कभी दरवाजे की तरफ लपकते। फिर लौटते और सूजन देखकर खामोश खड़े हो जाते। ऐसा लग रहा था कि चाहते हुए भी वे मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे थे।

दूसरे दिन सुबह मां ने मुझसे फिर पूछा, "पिंकी। बोलो बेटी अब क्या खयाल है ?" मैंने एक लंबी सांस ली और मां से नजरें चुराते हुए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे मुंह से 'हां' सुनकर मां कितनी खुश थीं। आसिफ से मुलाकात से सातवें दिन मेरी उनसे शादी पक्की हो गयी। उसी दिन प्रेस के लिए मैंने अपना बयान जारी किया, "अपने मजहबी फराएज का अहसास करते हुए और मां की ख्वाहिश की कद्र करते हुए मैंने अपनी मां बेगम नुसरत भुट्टो की गुजारिश पर शादी की रजामंदी जाहिर कर दी है। मेरी शादी मुझे मेरी सियासी जिंदगी से अलग नहीं करेगी। जिस तरह से कल मैं पाकिस्तान की अमानत थी, उसी तरह शादी के बाद भी उसी की अमानत रहूंगी। पाकिस्तान की अवाम के लिए मैंने जो मुहिम छेड़ी है, उसे मैं जिंदा रखूंगी और एक दिन पाकिस्तान में जम्हूरियत बहाल करवाकर ही दम लूंगी।"

—बेनजीर : डाटर आफ द ईस्ट
आत्मकथा
हमिश हैमिल्टन लंदन, पाउंड १२.९५
वितरक रूपा एण्ड कंपनी
अनुवाद : तारिक खान

चुटकी की चुटकियां
ज़िन्दगी की भोली-भाली मस्तियां
चुटकी पान मसाला प्यार के रिश्तों में एक अनोखी ताज़गी और मीठी-मीठी महक लाता है। हर मौके, हर महफ़िल में रंग जमाता है। सौंफ़, छुआरा और इलायची वाला चुटकी पान मसाला कितना है निराला!
अब नये सजधज के साथ नये आकर्षक पॉउच पैक में!
Chutki
प्यार का मस्ती भरा एहसास
चुटकी पान मसाला!

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

सेवानिवृत्तों की जागीर

तमाम रियायतों और सहायता के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड २२९७ करोड़ के घाटे में दबा जा रहा है। यदि इसका कारण, सिलसिलेवार तरीके से, राजनेताओं द्वारा बिजली बोर्ड पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को थोपा जाना नहीं है, तो और क्या है?

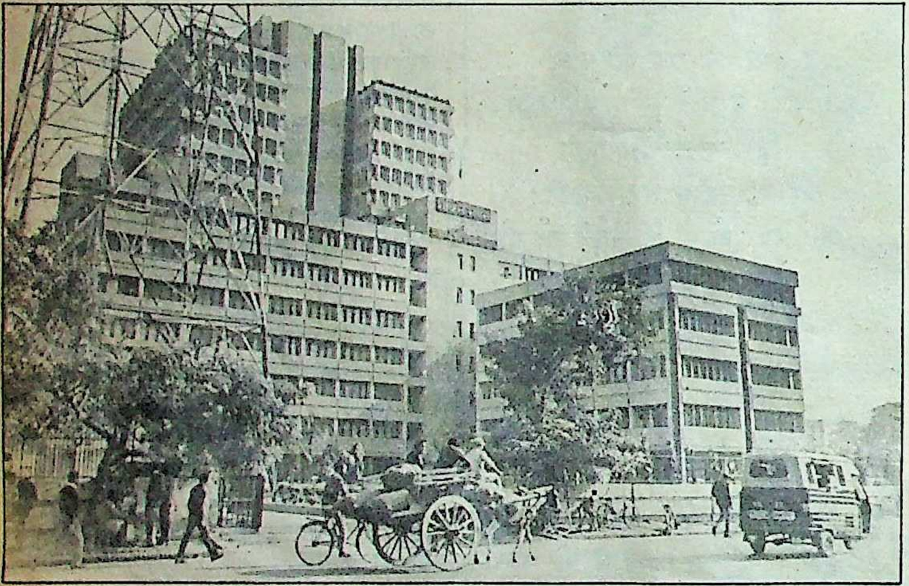

पुनरागत का स्वागत: उप्र राज्य विद्युत परिषद का मुख्यालय 'शक्ति भवन'

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम राज्य विद्युत परिषद की वर्ष-प्रतिवर्ष घटती माली हालत का नतीजा यह है कि प्रदेश को प्रकाशमान करनेवाला यह विभाग इस समय २२६७ करोड़ रुपए के समेकित घाटे में टिमटिमा रहा है। यह स्थिति तब है, जबकि अप्रैल '८८ में सरकार ने विद्युत परिषद की आर्थिक दयनीयता के कारण उस पर बकाया १९०० करोड़ रुपए का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया है। यही विभाग है जिसने अपनी बदइंतजामी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को महेंद्र सिंह टिकैत की भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले संगठित होने के लिए विवश किया। फलतः बिलों की वसूली थम-सी गयी है। विभाग को घाटे से उबारने के लिए वर्तमान अभियंता अधिकारियों को अनुभवहीन मानकर सेवानिवृत्त अधिकारियों को बागडोर थमायी गयी। बावजूद इन सब तिकड़मों के राज्य विद्युत परिषद की खस्ताहाली बढ़ती ही जा रही है।

बहाना उबारने का: राज्य विद्युत परिषद ने विभिन्न परियोजनाओं पर ३९८० करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश किया है। इसमें से ३८०० करोड़ रुपए राज्य सरकार से और शेष बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से बतौर कर्ज लिया गया है। विद्युत परिषद इस कर्ज का ब्याज भी दे सकने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा परिषद पर लगभग ४०० करोड़ रुपए की देनदारी चढ़ी हुई है। यह स्थिति बकाया बिलों (४५३.४४ करोड़ रु०) की वसूली में कोताही, विद्युत-चोरी (लगभग ३०० करोड़ रु०) की ही नहीं, संचालन एवं प्रशासन-तंत्र के गैरजिम्मेदाराना तौर-तरीकों की भी देन है। अनावश्यक खर्च, राजनीतिक हस्ती के चहेतों की भरती का वेतन-बोझ, परियोजनाओं में लेटलतीफी भी परिषद की आर्थिक जर्जरता बढ़ाने में सहायक रही है। इसे घाटे से उबारने, आर्थिक आधार मजबूत करने और उपभोक्ताओं को सुचारु आपूर्ति के नाम पर यहां कई किस्म की तरकीबें ईजाद की गयीं, लेकिन सबमें व्यक्तिगत लाभ की लालसा आड़े आती गयी। अनुभवी लोगों का सहयोग लेने के बहाने सेवानिवृत्त लोगों की भरती का सिलसिला इस कदर चालू हुआ कि आज इस विभाग के हर जिम्मेदार, अधिकारप्राप्त और कमाऊ पदों पर सेवानिवृत्तों की कब्जेदारी हो गयी है। एक ओर परिषद में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भरती पर रोक है, तो दूसरी ओर राजनीति में ऊंची पहुंच रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति जोरों पर है।

चहेते अध्यक्ष: अव्वल तो अध्यक्ष की कुरसी पर ही पिछले कई वर्षों से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की कब्जेदारी बनी हुई है। पहले इस पद पर आईएएस अधिकारी नियुक्त होता था। वर्ष १९५९ में स्थापित उप्र राज्य विद्युत परिषद के पहले अध्यक्ष बीबी लाल, आईएएस थे। १९६५ में बोर्ड में पहली बार अभियंता संवर्ग के लक्ष्मण देव को अध्यक्ष बनाया गया था। उनके त्यागपत्र दे देने पर विद्युत बोर्ड के इस सर्वोच्च पद पर सिंचाई विभाग के एसके जैन को थोप दिया गया। इसी के बाद इस पद पर विभिन्न नेताओं ने अपने चहेतों को प्रतिष्ठापित करना शुरू किया। १९६९ में शुरुआत प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह ने की, विद्युत परिषद के सेवानिवृत्त अधिकारी एसएन सिंह को बिजली बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर। चरण सिंह के हटने के बाद इस पद पर पुनः आईएएस अधिकारी आरके त्रिवेदी (जो बाद में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए) को बिठा दिया गया। इस पद पर आईएएस अधिकारियों की पुनर्प्रतिष्ठा को लेकर यहां के अभियंताओं ने १९७३ में आंदोलन किया। तब शासन ने यहीं के वरिष्ठ अभियंता अधिकारी एलबी तिवारी को बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। आपातकाल में परिषद के ही बीएन बालिगा इस पद पर रहे। उनके बाद यहीं के एएन भार्गव तथा आरएन भार्गव ने यह पद पाया। १९८१ में प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चौधरी चरण सिंह की तरह इस पद को सेवानिवृत्त लोगों की धरोहर बताते हुए, परिषद से ही सेवानिवृत्त हुए रणजीत कुमार सान्याल को अध्यक्ष पद सौंप दिया।

वीपी सिंह के बाद जब श्रीपति मिश्र मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठे, तो उन्होंने प्रदेश की सीमा लांघकर महाराष्ट्र राज्य विद्युत परिषद से अवकाशप्राप्त नारायण मिश्र को यह पद नजर कर दिया। १९८५ में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की बारी आयी, तो उन्होंने दिल्ली दरबार तक पहुंच रखनेवाले अनिरुद्ध कुमार शाह को यह पद दे दिया। ३ वर्ष तक के लिए यहां खपाये गये शाह ने एक माह पूर्व ही राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के चेयरमैन पद से अवकाश ग्रहण किया था। उन्होंने केंद्रीय ऊर्जामंत्री वसंत साठे की कृपा से यह पद हथियाया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद स्वायत्तशासी संस्था है। इसके बोर्ड में अध्यक्ष सहित ७ सदस्य हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर भी शाह वेतन-लाभ और पद का मोह तज नहीं सके। लिहाजा उन्होंने फिर केंद्रीय ऊर्जामंत्री की परिक्रमा की। बोर्ड के ऊपर एक और बोर्ड 'ऊर्जा सलाहकार बोर्ड' गठित किया गया और उसके चेयरमैन पद पर शाह को 'ऐडजस्ट' कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के सचिव, शैलेंद्र दुबे का आरोप है, "शाह के कार्यकाल में विद्युत परिषद की प्रगति में ठहराव आ गया। बावजूद इसके, उनके

कार्यकलापों की समीक्षा को दरकिनार कर ऊपरी पहुंच पर केवल उन्हें 'ऐडजस्ट' करने के लिए 'ऊर्जा सलाहकार बोर्ड' का गठन कर उसमें उन्हें सर्वेसर्वा का पद दे दिया गया, जबकि विद्युत परिषद के नियम १९४८ के तहत ऐसे किसी बोर्ड का प्रावधान उल्लिखित नहीं है।"

बोर्ड की अंदरूनी जानकारी रखनेवालों के अनुसार शाह को विद्युत परिषद में बनाये रखने की मजबूरी यह है कि वे विदेशों से 'डील' (सौदेबाजी) करने में माहिर हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की २ × ५०० मेगावाट की अनपारा-बी (मिर्जापुर) परियोजना भी विदेशी सहयोग पर आधारित है। सूत्र बताते हैं कि जब तक अनपारा की विदेशी 'डील' फाइनल नहीं हो जाती, तब तक शाह की कुरसी विद्युत परिषद में जमी रहेगी। यह 'डील' जापान से होनी है।

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आकंठ घाटे में डूबे प्रदेश के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम की आर्थिक बुनियाद का ही अता-पता नहीं है? परिषद की संपत्ति आखिर है कितनी?

दरबार की दुआ: अनिरुद्ध कुमार शाह

अनर्हता ही अर्हता: बीबी जिंदल

किस मंत्री के जिम्मे क्या काम है, यह खुद मंत्री को ही नहीं पता। नरेंद्र सिंह जहां विद्युत विभाग पर अपने एकाधिकार के लिए प्रयासरत हैं, वहीं रामऔतार दीक्षित, कोकब हमीद अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग छेड़े हुए हैं।

शाह द्वारा खाली किये गये राज्य बिजली बोर्ड का अध्यक्ष पद तब के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और ऊर्जा राज्यमंत्री प्रमोद तिवारी की कृपा से भूपाल सिंह को मिला जो एक ही महीने पहले बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्तों की परिषद में पुनर्नियुक्ति का मापदंड भी काफी विचित्र है। लखनऊ, बनारस और मेरठ के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के साथ उनसे कनिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त हुए अभियंताओं को उनके सलाहकार के रूप में रखा गया है। लाभ की बात यह है कि इन सलाहकारों को उन्हीं के निवास स्थल वाले जिले के मंडलीय मुख्य अभियंता के साथ नत्थी किया गया, साथ ही अपना वेतन, यात्रा-व्यय आदि का बिल पास करने का भी अधिकार इन सलाहकारों को प्रदत्त कर उपकृत किया गया है। परिषद के ही अतिरिक्त सचिव समरथ सिंह वर्ष १९८७ में सेवानिवृत्त होने के बाद अब यहीं विशेष कार्य अधिकारी का पद हासिल किये हुए हैं।

बुनियाद लापता: अनुभव के नाम पर सेवानिवृत्तों की भीड़ विद्युत परिषद की गिरती साख को तो बचा नहीं सकी, उलटे इनके वेतन-बोझ से चरमराती अर्थव्यवस्था दरकने लगी है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आकंठ घाटे में डूबे प्रदेश के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम की आर्थिक बुनियाद का ही अता-पता नहीं है? परिषद की संपत्ति आखिर है कितनी? यह पता लगाने के लिए दिल्ली की 'मेसर्स टाटा इकानामिक सर्विस' को ८५ लाख रुपए का ठेका दिया गया है। इस कार्य में भी एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एसएल शर्मा को इस फर्म का सलाहकार नियुक्त किया गया। मजे की बात तो यह है कि ये सलाहकार महोदय अलीगढ़ के बाशिंदे हैं और घर पर ही बैठकर दिल्ली की इस फर्म को सलाह देते रहते हैं। लगभग ७५०० रुपए का वेतन-लाभ अर्जित करने वाले शर्माजी टेलीफोन, यात्रा-भत्ता अपने आप स्वीकृत करते हैं। इनका वेतन अलीगढ़ के अधीक्षण अभियंता के जिम्मे है।

यह ठेका तब दिया गया है, जबकि विद्युत परिषद में खुद ब्रजभूषण जिंदल पिछले कई वर्षों से बोर्ड के सदस्य वित्त और लेखा, के पद पर काबिज हैं। संपत्ति का पता लगाने का जो कार्य ठेके पर दिया गया, वह कार्य वस्तुतः जिंदल का ही है। परिषद में जिंदल सर्वाधिक विवादास्पद अधिकारी माने जाते हैं। जिंदल के पास वह अर्हता नहीं है जो इस पद के लिए जरूरी है। इंडियन आडिट ऐंड एकाउंट्स सर्विस के लोगों को ही नियमानुसार सदस्य वित्त एवं लेखा का पद दिया जा सकता है, लेकिन १९७९ में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारसी दास ने जातीय आधार पर जिंदल को यह पद देकर इस नियम को बालाएताक रख दिया था। उनके हटने के बाद जिंदल भी हटाये गये और नियमानुसार अर्हता रखने वाले नीलांबर श्रीवास्तव को सदस्य, वित्त एवं लेखा के पद पर लाया गया। बाद में श्रीवास्तव प्रदेश के मुख्य लेखाकार होकर यहां से चले गये, तब बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष रणजीत कुमार सान्याल, रेलवे विभाग के एससी मुकर्जी को प्रतिनियुक्ति पर यहां इस पद पर ले आये। इस बीच जिंदल अपनी गोट फिट करते रहे। जिंदल ने अंततः १९८४ में पुनः सदस्य वित्त एवं लेखा का पद प्राप्त कर लिया जहां वे अभी तक काबिज हैं।

नया कदम: बकायेदारों, विद्युत चोरी करनेवालों तथा विभागीय मामलों के न्यायिक मसलों के लिए विद्युत परिषद में उच्च न्यायिक सेवा के एक अधिकारी की नियुक्ति हुई है। इनका कार्य वैसे तो विद्युत परिषद की ओर से दायर मुकदमों में परामर्श देना है, लेकिन अमूमन उनके इस दायित्व पर भी बाहरी लोगों ने अपनी गोट फिट कर रखी है। परिषद के न्याय विभाग का कार्य बस इतना भर रह गया है कि वह परिषद के मुकदमों की पैरवी करने के लिए किसी वकील को ठेका दिला देता है।

जिम्मेदार अधिकारियों के फौजफाटे के अलावा इस बार नारायण दत्त तिवारी ने विद्युत विभाग के लिए चार मंत्री बनाये हैं। इनमें नरेंद्र सिंह कैबिनेट स्तर के, रामऔतार दीक्षित व कोकब हमीद राज्य स्तर के मंत्री और श्रीमती रीना कुमारी उपमंत्री हैं। किस मंत्री के जिम्मे क्या काम है, यह खुद मंत्री को ही नहीं पता। नरेंद्र सिंह जहां विद्युत विभाग पर अपने एकाधिकार के लिए प्रयासरत हैं, वहीं रामऔतार दीक्षित, कोकब हमीद अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग छेड़े हुए हैं। इन दोनों मंत्रियों की शिकायत है कि विभाग में उनकी कोई नहीं सुनता। इन दोनों से अच्छी हैसियत तो उपमंत्री श्रीमती रीना कुमारी को मुख्यमंत्री के वरदहस्त की बदौलत हासिल है। ऐसे में चार मंत्रियों वाली राज्य विद्युत परिषद की माली हालत सुधरने की बात करना ही फिजूल है।

—सुरेश द्विवेदी

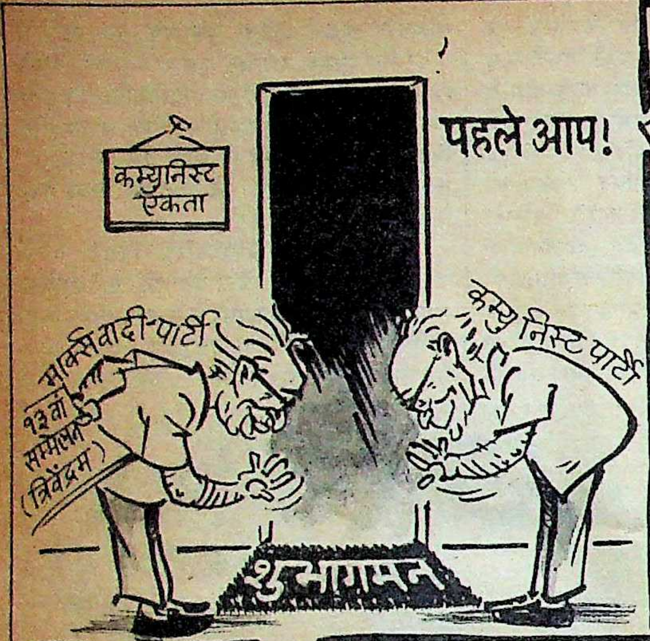
पहले आप!
कम्युनिस्ट एकता
मार्क्सवादी-पार्टी
13वां सम्मेलन (त्रिवेंद्रम)
कम्युनिस्ट पार्टी
शुभागमन

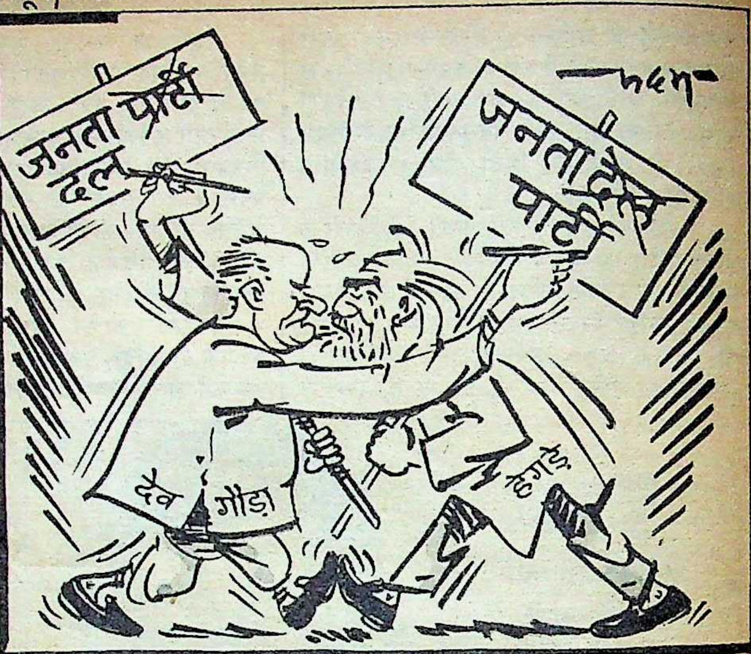
कदम
जनता पार्टी दल
जनता दल पार्टी
देव गौड़ा
हेगड़े

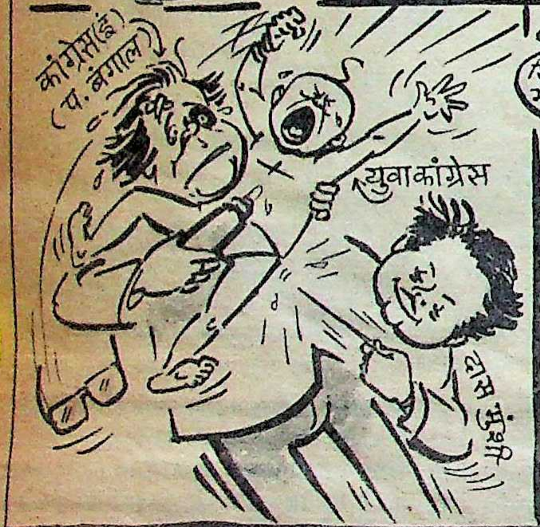
कांग्रेस(इ) (प. बंगाल)
युवा कांग्रेस
दास मुंशी

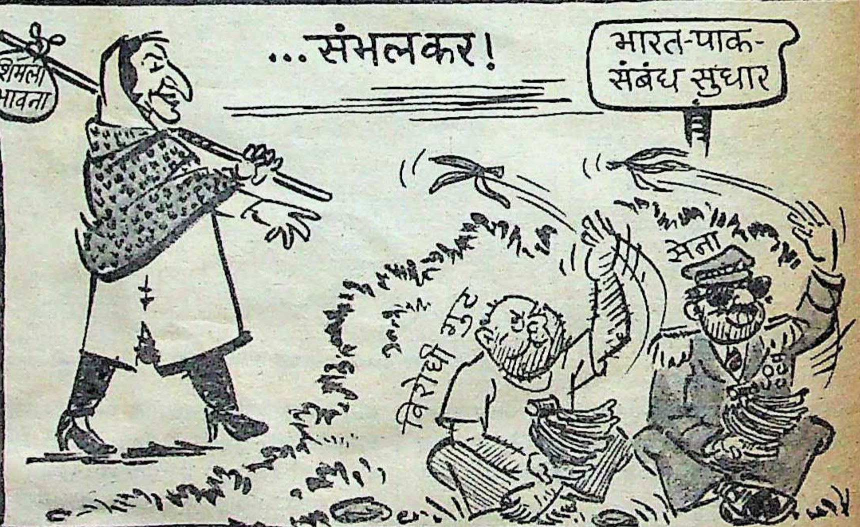
...संभलकर!
शिमला भावना
भारत-पाक-संबंध सुधार
विरोधी गुट
सेना

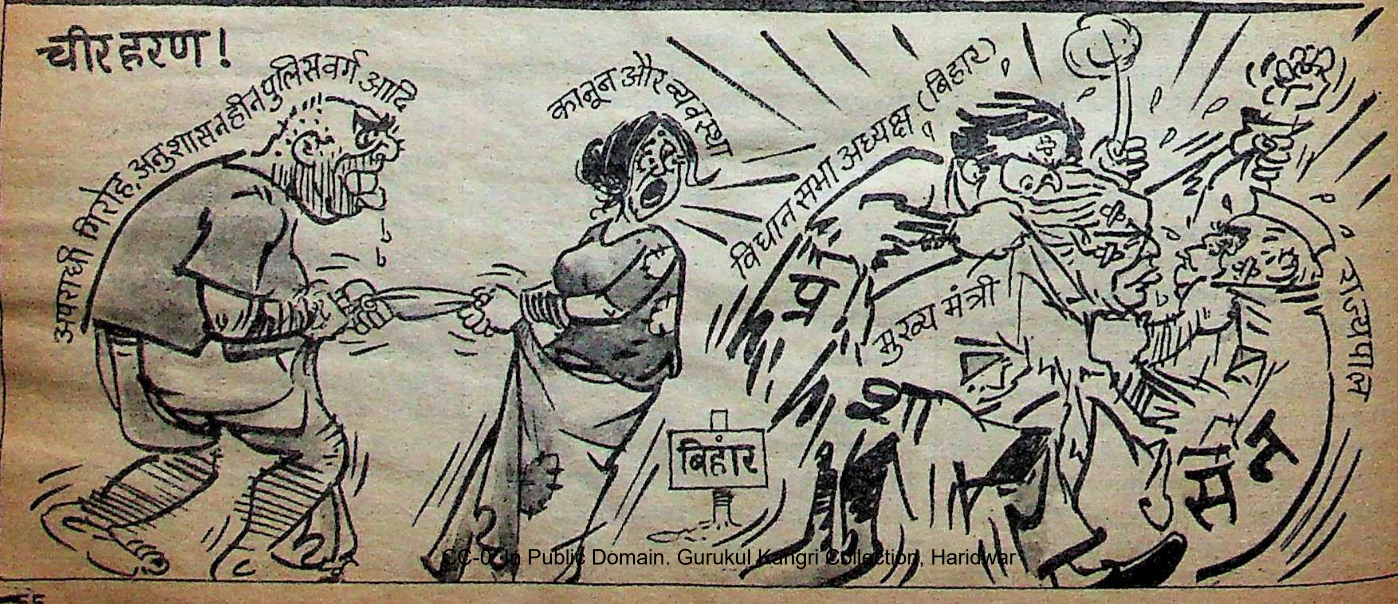
चीरहरण!
अपराधी गिरोह, अनुशासनहीन पुलिसवर्ग आदि
कानून और व्यवस्था
विधान सभा अध्यक्ष (बिहार)
मुख्य मंत्री
राज्यपाल
प्र
शा
स
न
बिहार

जीवन रेखा

अस्पतालों की असलियत को उजागर करने की पहल

'जीवन रेखा' के एक दृश्य में केके रैना और तन्वी आजमी

विजया मेहता होने का एक अर्थ होता है और इस अर्थ की सार्थकता है—हर मंगलवार को प्रदर्शित होनेवाला सीरियल 'जीवन रेखा'। अगर विजया मेहता नहीं होतीं, तो 'जीवन रेखा' को मंडी हाउस 'एप्रूव' नहीं करता। क्योंकि पहले इसकी योजना को, फिर पायलट को मंडी हाउस सखेद वापस कर चुका था और उसके बाद तब परिदृश्य में आयी थीं विजया मेहता। वे 'जीवन रेखा' की स्क्रिप्ट को दुबारा लेकर जब मंडी हाउसं पहुंचीं, तब मंडी हाउस के अधिकारियों में उन्हें वापस लौटाने की हिम्मत नहीं थी। न केवल १३ के बजाय २२ एपीसीडों की तुरंत मंजूरी दे दी गयी, बल्कि इसका प्रसारण भी शिड्यूल कर दिया गया। इस तरह शुरुआत हुई अस्पतालों की जिंदगी को दूरदर्शन के छोटे परदे पर उजागर करने की।

शुरुआत : सीरियल की शुरुआत अस्पताल में छह महीने के इंटर्नशिप पर आनेवाले छह प्रशिंक्षु डाक्टरों से होती है, जिनके माध्यम से अस्पताल की भीतरी जिंदगी परत-दर-परत खुलती जाती है। इनमें से एक हैं—डा० प्रवीण (केके रैना)। वे मानसिक धरातल पर अधिकता की हद तक संवेदनशील हैं, तो डा० माधुरी आचार्य (तन्वी आजमी) अस्पताल में भरती रोगियों के साथ दोस्ताना माहौल पैदा करने तथा उनके लिए डाक्टरी जरूरतों के साथ-साथ मानसिक राहत प्रदान कर उनकी चिकित्सा करने की पक्षधर हैं। डा० जोशी (मंगेश कुलकर्णी) अंतर्मुखी हैं और मानसिक तनाव तथा अंतर्द्वंद्व की पीड़ा को झेलते रहने को विवश हैं—चाहकर भी विरोध नहीं कर पाते। बलात्कार की शिकार बसंती की पीड़ा उन्हें गहराई तक मथती है, लेकिन घायल बलात्कारी, जिसकी उस लड़की के भाइयों ने पिटाई कर दी थी, को सामने पाकर भी मन के विरोध को उस पर प्रकट नहीं कर पाते। इसी तरह तीन और डाक्टर हैं—विभिन्न शख्सीयत, विचारधाराओं और मानसिकता के स्वामी। और इन्हीं के बीच हैं डा० राव (एके हंगल), जो अस्पताल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होने के साथ-साथ इन्टर्न डाक्टरों को प्रशिक्षण देने के भी इंचार्ज हैं।

इन सकारात्मक पात्रों के साथ-साथ अस्पताल कर्मचारियों-डाक्टरों का नकारात्मक स्वरूप भी है। वे डाक्टर जो अस्पताल में भरती संपन्न मरीजों के विभिन्न अवयवों की जांच बाहर की टेस्ट एजेंसियों से कराकर उनसे कमीशन भी लेते हैं और रोगियों को उनकी सही स्थिति से बेखबर रखते हुए 'अतिरिक्त कमाई' के लिए उनके इलाज को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही रोगियों में एक रोगी है—उद्योगपति सोलंकी (शफी ईनामदार), जिसका चेकअप करने पर डा० प्रवीण को पता चलता है कि उसको लीवर कैंसर है और वह सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है। अस्पताल के दूसरे डाक्टरों ने जान-बूझकर उसे उसकी बीमारी के बारे में आगाह नहीं किया और झूठे चेकअप तथा परीक्षणों के नाम पर अच्छी 'कमाई' करते रहे। अंततः सोलंकी को उसके भयावह रोग की सूचना देने की जिम्मेदारी प्रशिक्षु डाक्टर प्रवीण पर सौंपी जाती है, जो कहता है, "मैंने दवाओं के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन यह नहीं सीखा कि किस तरह मरीज को बतला सकूं कि किस तरह जिंदगी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान भर रह गयी है।"

इस तरह के डाक्टरों के साथ अस्पताल के भ्रष्ट कर्मचारियों का एक और अंतहीन काफिला है जिसका प्रतीक है वार्ड ब्वाय (चंदू पारखी), जो जाली या नकली बिल रोगियों को थमाकर अतिरिक्त कमाई करता रहता है। मरीजों के अस्पताल की तरफ से मुहैया होनेवाले पौष्टिक भोजन, दूध, फल तथा दवाएं आदि सामग्री किस तरह उन तक पहुंचने से पहले ही अस्पताल कर्मचारियों के बैग या उदर तक पहुंच जाती हैं, इसका विजया मेहता ने बड़ी बेबाकी से चित्रण किया है।

तह तक पहुंचने की कोशिश : विजया मेहता अस्पताल, डाक्टर तथा कर्मचारियों की जिंदगी से उठकर मरीजों की जिंदगी की तह तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। बलात्कार की शिकार बसंती अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बतलाना चाहती है, लेकिन उसकी मां उसे इसलिए बरजती है कि अत्याचार सहना उनकी नियति है और विरोध करने पर उत्पीड़न की सजा उनका प्रारब्ध। इसीलिए बलात्कारी बड़ी सहजता से डा० जोशी से कह जाता है, "इस तरह के अपराधों की शिकायत न तो पुलिस स्टेशन में होती है और न ही अदालतों में गवाही।" और विजया मेहता बड़ी संजीदगी से इस संवाद द्वारा अनियंत्रित्त बलात्कार का काला चेहरा दर्शकों को दिखला जाती हैं और यह सिर्फ उनके ही वश की बात है। देवेन खोटे इस सीरियल को बनाने के उद्देश्य के बारे में कहते हैं, "दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षित करना ही हमारा उद्देश्य रहा है।" वे कहते हैं, "इस सीरियल के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हम इंसान को सिर्फ इंसान के नजरिये से, इंसान की ही तरह से देखें। इसलिए इसमें ब्लड ट्रांस-फ्यूजन, नेत्रदान जैसे आम विषय को लिया गया है, तथा दूसरी बातों को भी। जैसे सड़क पर गिर पड़े एक बेहोश लड़के को लेकर एक गरीब युवक अस्पताल आता है और डाक्टर द्वारा नाम पूछने पर कह बैठता है— 'मैं अपना नाम नहीं बतलाऊंगा, मुझे झंझट में नहीं फंसना है। मेरा जो कर्तव्य था कर दिया, बस।' इस एपीसोड के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग सिर्फ झंझट के भय से ही अपने फर्ज से मुंह न मोड़ें, सामने आयें। जब ऐसे लोगों का काफिला सामने आने की हिम्मत-अफजाई करने लगेगा, तो यह 'झंझट में फंसने की कोताही' अपने आप ही खतम हो जायेगी।"

—सुषमा त्रिपाठी एवं बंबई ब्यूरो

केबिल टीवी

बड़े बजट की फिल्मों के लिए खतरे की घंटी

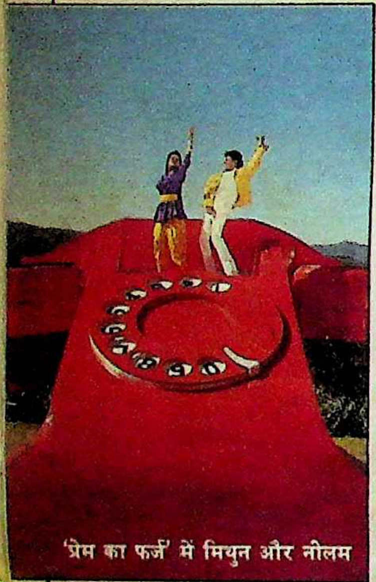

'प्रेम का फर्ज' में मिथुन और नीलम

छाया : एन प्रसाद

टीवी, वीडियोपाइरेसी और डिश एंटिना से तो फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का चूना लग रहा था, लेकिन आम दर्शकों को कम पैसे में ही घर बैठे एक-से-एक अच्छी फिल्में देखने को मिल जा रही थीं। साथ ही परिवारवालों को सिनेमाघरों की गुंडागर्दी और फिकरेबाजी से भी निजात मिल रही थी। इधर जब से केबिल टीवी का आगमन हुआ है, तब से फिल्म उद्योग की हालत और भी खस्ता हो रही है, क्योंकि बड़े बजट की फिल्में परदे पर लगते ही उतर जा रही हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए निर्माता-निर्देशक और अभिनेता कैसी रणनीति अपना रहे हैं?

फिल्म इंडस्ट्री के बाक्स आफिस पंडित मनमोहन देसाई की बहुप्रचारित फिल्म 'गंगा जमुना सरस्वती' का २३ दिसंबर '८८ की रात भव्य प्रीमियर होना ही था कि अड़ोस-पड़ोस के लोगों ने यह कहकर चौंका दिया कि हम लोगों ने तो केबिल टीवी पर 'गंगा जुमना सरस्वती' पहले ही देख ली। प्रदर्शन के प्रथम सप्ताह में इस फिल्म के टिकट ब्लैक में ५० रुपए से १०० रुपए (प्रीमियर की रात) में बिके थे तथा पूरे सप्ताह के लिए सभी सिनेमाघरों के बाहर हाउस फुल के बोर्ड लटक गये थे, इससे फिल्म इंडस्ट्री के बाक्स आफिस पंडितों के मन में यह आशा जगी थी कि वर्ष के अंत में प्रदर्शित 'गंगा जमुना सरस्वती' बहुसितारीय फिल्मों के डांवांडोल भविष्य को संभाल लेगा।

मनमोहन देसाई (निर्देशक), एस रामानाथन (निर्माता) तथा अमिताभ बच्चन (नायक) के बाक्स आफिस जादू के प्रबल आकर्षण के ही कारण वीडियो पार्लरों ने फिल्म के वीडियो कैसेटों का धुआंधार आर्डर दे दिया था और कैसेट का किराया ५ रुपए से बढ़ाकर ५० और फिर ७० रुपए कर दिया था। लेकिन अचानक जैसे सारा अंकगणित ही बदल गया, 'गंगा जमुना सरस्वती' का बिजिनेस १०० प्रतिशत से अचानक घट कर दूसरे सप्ताह में ७५ प्रतिशत तथा तीसरे सप्ताह में ६० प्रतिशत हो गया। मनमोहन देसाई की कोई भी फिल्म कभी भी इस बुरी तरह से फ्लाप नहीं हुई थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सभी फिल्मों ने ८ करोड़ से १२ करोड़ रुपए (निर्माण लागत से दस गुना अधिक) का औसत बिजिनेस किया था।

क्यों हुआ, कैसे हुआ ? : "यह सब केबिल टीवी का कमाल था," एक फिल्म वितरक ने 'माया' को बतलाया, "मनमोहन देसाई जैसी फिल्में बनाते थे और अमिताभ बच्चन जैसी ऐक्टिंग करते थे, सबने वैसा ही कुछ 'गंगा जमुना सरस्वती' में किया, लेकिन ४० प्रतिशत दर्शकों ने इसे केबिल टीवी पर तथा ३० प्रतिशत ने वीडियो पर देख लिया। २५ प्रतिशत ने फिल्म में कोई रुचि ही नहीं दिखलायी, सिर्फ ५ प्रतिशत ही सिनेमाघर तक गये। यह वह दर्शक समुदाय था, जो हर तरह की फिल्में टिकट खरीद कर देखने का आदी है। अब ढाई करोड़ रुपए की लागत से बनी फिल्म पांच प्रतिशत दर्शकों के बल पर कैसे चल सकती है भला ?"

'दयावान' की अप्रतिम असफलता से क्षुब्ध निर्माता-अभिनेता-निर्देशक फीरोज खान का कहना था, "मैंने बड़ी लगन, कड़ी मेहनत तथा काफी धन खर्च कर कम-से-कम समय में 'दयावान' का निर्माण किया था। आम दर्शक इस तरह की फिल्मों में जिस तरह के मनोरंजन-तत्वों की मांग करते हैं, वह सब कुछ फिल्म में था। आखिर बाक्स आफिस पर सफलतम फिल्में

गोविंदा और किमी काटकर

बनाने का मेरा भी दो दशक पुराना अनुभव है और दर्शकों की रुचि में इधर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन जब दर्शकों को आराम से घर बैठे वीडियो या केबिल टीवी के माध्यम से मनचाहे सितारोंवाली फिल्में देखने को मिल जायें, तो वे घर से सिनेमाघर जाने और रुपए खर्च करने की तकलीफ भला क्यों उठायें?"

बड़े-बड़े सितारोंवाली छह-छह नायक और नायिकाओंवाली बाक्स आफिस हिट फिल्में बनाने के लिए मशहूर निर्माता-निर्देशक राज कुमार कोहली, जिनकी दो बहुसितारीय फिल्में ('साजिश' एवं 'इंतकाम') पिछले वर्ष बुरी तरह से फ्लाप हो गयी थीं, ने 'माया' को बतलाया, "टैक्सों की मार तथा वीडियोपाइरेसी से अभी तक फिल्म इंडस्ट्री खस्ताहाल थी ही, अब डिश एंटिना और केबिल टीवी ने उसकी रीढ़ ही जैसे चटका दी है।" एक वीडियो पार्लर में जहां आम तौर पर १० से २० दर्शक तथा एक घर में जहां सात से दस लोग वीडियो पर फिल्में देखते थे, वहीं केबिल टीवी पर बीस हजार दर्शक प्रतिदिन दो-तीन फिल्में देखते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिश एंटिना तथा केबिल टीवी की व्यवस्था झोंपड़पट्टियों, चालों तथा आम आदमी की रिहायशी बस्तियों में पोश इलाकों की बनिस्बत ज्यादा हो गयी है और इन बस्तियों के रहनेवाले लोग ही असली फिल्म दर्शक होते हैं, जो सिनेमाघरों पर घंटों लाइनें लगा कर, ब्लैक में टिकट लेकर फिल्में देखा करते थे, क्योंकि उनके मनोरंजन का एकमात्र सस्ता साधन सिनेमा ही है, जो सिर्फ उन्हें सिनेमाघरों में ही मुहैया होता था, और अब उन्हें घर पर मुहैया होने लगा है। इसके लिए उन्हें न तो वीसीआर खरीदना पड़ता है और न ही दूसरे झंझट उठाने पड़ते हैं। बस हर माह ३० से ७५ रुपए प्रतिमाह शुल्क देना पडता है।

लगभग एक दशक पूर्व जब केबिल टीवी तथा डिश एंटिना ने हालीवुड, जापान, फ्रांस तथा ब्रिटेन के सिनेमा व्यवसाय पर हमला किया था, तो वहां की फिल्म उद्योग व्यवस्था एक क्षण के लिए चरमरा उठी थी। इसका धक्का सिर्फ फिल्म उद्योग को ही नहीं लगा था, बल्कि वहां का वीडियो कैसेट उद्योग भी बेतरह प्रभावित हुआ था, जिसने (वीडियो पार्लर) फिल्म उद्योग की हालत चरमरा दी थी। वीडियो उद्योग के हमले से बचने के लिए जहां ब्रिटेन और फ्रांस की फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्मों के साथ-साथ वीडियो फिल्में बनाना शुरू कर दिया था, वहीं हालीवुड ने वीडियो कापीराइट कानून को एक नया जामा पहनाने तथा उसका सख्ती से पालन करना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने 'स्टारवार्स', 'निंजा' जैसी फिल्में और भूत-प्रेत की रोमांचक फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया था जिसका आनंद सिर्फ सिनेमाघर में ही उठाया जा सकता था।

इसी तरह जापानी फिल्म उद्योग ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया—फिल्मों में सेक्स तथा हिंसा को अति क्रूर रूप में फिल्माना शुरू किया जिसे आमतौर पर पारंपरिक जापानी परिवार घर में परिवार के साथ देखना नापसंद करता था। दूसरे, ऐसी फिल्मों का आनंद टीवी के छोटे परदे के बजाय अत्याधुनिक साउंड सिस्टम युक्त सिनेमाघरों के विशाल परदे पर देख कर ही उठाया जा सकता था।

"भारी करों, वीडियो तथा केबिल टीवी के कारण कभी हर वर्ष जापान में बननेवाली औसतन छह सौ फिल्मों की संख्या अचानक घट कर ६० से ७० ही रह गयी थी। ऐसे में अप्रत्याशित संकट से बचने के लिए जापानी फिल्म निर्माताओं ने खुद ही यह रास्ता तलाश लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि संचार माध्यम में होनेवाली वैज्ञानिक क्रांतियों को यों ही अनदेखा नहीं किया जा सकता।" कुछ समय पहले एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में यह बात प्रख्यात जापानी निर्देशक अकीरा कुरुसोवा ने 'माया' को बतलायी थी।

"लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते", एक बंबइया फिल्म निर्माता ने 'माया' को बतलाया, "इस तरह की फिल्मों को पहले तो सेंसर प्रतिबंधित कर देता है, अगर काफी कट-पिट कर फिल्म किसी तरह से सिनेमा घर के परदे तक पहुंची भी, तो मशरूम की तरह उग आयी

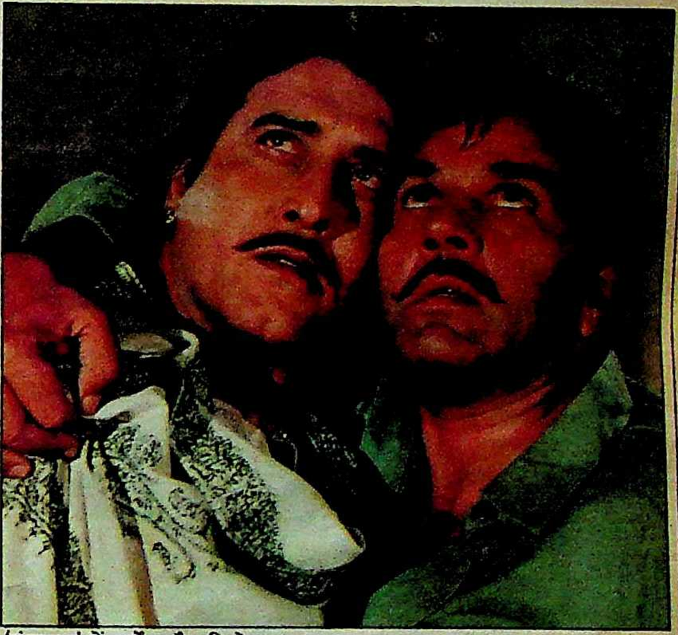
'बंटवारा' में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना

'दयावान' में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना

मनोरमा

फरवरी-प्रथम अंक

दावत सत्कार विशेषांक

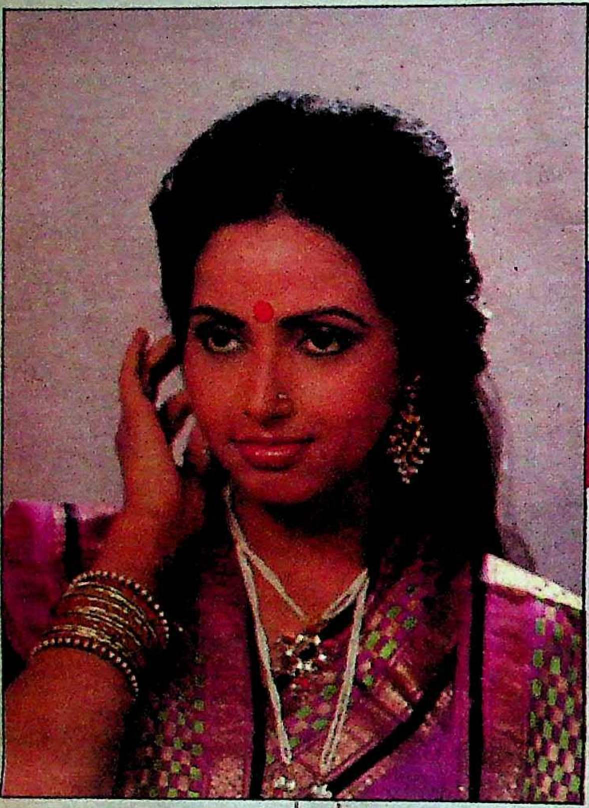

दावत और मेजबानी
के हुनर बताए
मेहमानी के रंग जमाए।

सौ से भी अधिक व्यंजन विधियां
हर मौके के लिये

प्रमुख आकर्षण

कम खर्च में बढ़िया दावत
किशोर-किशोरियों की पार्टी
स्पेशल दावतों के लिए चार मेनू
किटी पार्टी हो या ताश की दावत
फौजी सत्कार

अन्य रोचक लेख :

'मैं न भूलूंगी दावत की वह शाम'
परखिए कितनी भाग्यशाली हैं आप?

आवरण कथा

दिल जीतने की कला

साथ ही हास्य-व्यंग्य, कहानियां तथा अन्य सभी स्थाई स्तंभ

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित करायें

तमाम तथाकथित सामाजिक संस्थाओं को पोस्टर फाड़ने, सिनेमाघरों में घुसकर तोड़-फोड़ करने या सिनेमाघरों के बाहर प्रदर्शन कर सुर्खियों में बने रहने का भरपूर मौका मिल जाता है। वे इस बात के लिए आंदोलन नहीं चलाते कि सरकार ऐसी फिल्में बनने के कारणों को दूर करे या लोगों में इस बात के जागरण के लिए भी वे आंदोलन नहीं करते कि लोग अच्छी फिल्में देखें। न ही वे केबिल टीवी संचालकों तथा वीडियो पार्लरों के विरुद्ध कभी कोई आंदोलन करते हैं।''

लेकिन 'कच्ची कली' से लेकर 'पहला पुरुष पहली औरत' आदि सेक्स प्रधान फिल्मों की व्यावसायिक सफलता ने सेक्स प्रधान फिल्मों के निर्माण को निरंतरता प्रदान की। एक ऐसी ही फिल्म बनानेवाले निर्माता ने बतलाया, ''सेक्स प्रधान फिल्में एक तो नये कलाकारों तथा निर्माण लागत कम होने के कारण जल्दी बनती हैं और वितरकों द्वारा खरीद ली जाती हैं, दूसरे भारतीय परिवार कभी भी ऐसी फिल्मों को वीडियो कैसेट या केबिल टीवी पर देखना पसंद नहीं करते, इसलिए इनकी वीडियो कैसेट की मांग कम होती है। फिर अगर ये फिल्में सिनेमाघरों में एक सप्ताह भी हाउस फुल हो गयीं या दो-तीन सप्ताह मैटिनी शो में भी ठीकठाक चल गयीं, तो निर्माता की लागत और वितरक का पूरा इंस्टालमेंट निकल आता है। लेकिन अगर अमरीका, फ्रांस, ब्राजील, स्वीडेन आदि देशों की तरह इस तरह की फिल्मों का प्रदर्शन रात ११ बजे के बाद केबिल टीवी पर विवाहितों एवं वयस्क दर्शकों के लिए किया जाने लगा, तो हम भी संकट में फंस जायेंगे और फिल्म निर्माण की रही-सही आशा भी खतम हो जायेगी।''

कानूनी विसंगतियां: राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम की प्रबंध निदेशिका श्रीमती मालती तांबे वैद्य का कहना था, ''बहुसितारीय फिल्मों तथा दूसरी फिल्मों के लगातार असफल होते रहने के कारण फिल्म उद्योग पर जो संकट गहराया है, वह केबिल टीवी के कारण है। सैटेलाइट टीवी के आगमन से यह संकट और भी गंभीर हो जायेगा। मौजूदा कानूनों की विसंगतियों के कारण केबिल टीवी संचालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती।''

फिल्म निर्माता विजय रेड्डी का कहना है, ''दरअसल, आपसी झगड़ों तथा फिल्म इंडस्ट्री में घुस आयी राजनीति तथा राजनीतिक सौदेबाजी के कारण हम वर्तमान संकट का योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर एक तरफ सरकारी बंदिशों, अप्रत्याशित तथा अयथार्थपरक करों का बोझ है, तो दूसरी तरफ दूरदर्शन, वीडियोपाइरेसी, केबिल टीवी, डिश एंटिना, टीवी सीरियलों तथा टीवी फिल्मों आदि ने खतरा पैदा कर दिया है। उस पर मजेदार बात यह कि हर कोई हमारा शोषण हमारी ही बनायी फिल्मों को लेकर कर रहा है। अलग से बनायी गयी वीडियो फिल्मों तथा टेलीफिल्मों की कोई मांग आम दर्शक में नहीं है। वीडियो पार्लर तथा केबिल टीवीवाले हमारी ही फिल्मों को चोरी-छिपे दिखलाकर लाखों रुपए, बिना कोई लागत गांठ से लगाये, कमा रहे हैं और हम फिल्म निर्माता बेबसी से अपने को लुटते हुए देख रहे हैं कि पुलिस के पास वीडियो व केबिल टीवी चोरों को पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है और सरकार है कि सब कुछ जानते हुए भी अलग से कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस समय केबिल टीवी हमारी दुश्मन नंबर एक है और अगर इसके विरुद्ध कोई कड़ा कानून नहीं बनाया गया, तो यह समूचे फिल्म उद्योग को ध्वस्त कर देगा।''

हमले-दर-हमले: फिल्म निर्माताओं ने केबिल टीवी के इस हमले से बचने के लिए अदालतों की शरण लेनी शुरू कर दी है। पिछले दिनों राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक ऐसे ही फैसले कि 'केबिल टीवी वीडियो कैसेट की तरह सिर्फ घर पर फिल्म देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह फिल्म प्रदर्शन कानूनों का व्यावसायिक शोषण है' फिल्म निर्माताओं-वितरकों तथा प्रदर्शनों को थोड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने निजी तौर पर केबिल टीवी संचालकों का पता लगा कर उनके विरुद्ध पुलिस से छापे मरवाना शुरू कर दिया है। इसमें फिल्म प्रदर्शन संबंधी कानून की एक धारा उनकी मदद करती है। इस धारा के तहत फिल्मों के चोरी किये गये वीडियो कैसेट को व्यावसायिक रूप से दिखाने पर तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

फिल्म निर्माताओं की पहल पर ३ जनवरी '८६ को बंबई पुलिस ने ४८ घंटे के भीतर बांद्रा, घाटकोपर तथा पंतनगर में चल रहे तीन केबिल टीवी नेटवर्क पर छापा मारकर चार केबिल टीवी संचालकों को गिरफ्तार किया। ये नेटवर्क 'अदालत' तथा 'दरवाजा' जैसी फिल्मों का प्रदर्शन केबिल टीवी पर कर रहे थे। इसके पहले बंबई पुलिस ने लोखंडवाला कांप्लेक्स, बांद्रा, अंधेरी तथा दूसरे उपनगरों में भी छापे मार कर केबिल टीवी संचालकों को गिरफ्तार किया, जो उस समय 'इंतकाम', 'धर्मयुद्ध', 'आ गले लग जा', 'इंसपेक्टर ईगल' तथा दूसरी फिल्में दिखला रहे थे।

केबिल टीवी के बढ़ते खतरों को देखते हुए कतिपय जाने-माने फिल्म निर्माताओं तथा वीडियो फिल्म निर्माताओं ने इस खतरे से निजात पाने के लिए एक संस्था 'इंडियन फेडरेशन अगेंस्ट कापीराइट थेफ्ट' (इनफैक्ट) का गठन किया है, जो आवश्यक कानून बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के अलावा केबिल टीवी संचालकों तथा नेटवर्क केंद्रों का पता लगाकर वर्तमान कानून के तहत (अनधिकृत रूप से चोरी के फिल्म प्रिंट दिखलाने पर) पुलिस के छापे की व्यवस्था करेगा। कुछ वर्ष पहले वीडियोपाइरेसी को रोकने के लिए फिल्म निर्माताओं ने इसी रास्ते को अपनाया था। एक जाने-माने वीडियो फिल्म निर्माता नारी हिरा ने तो अवकाशप्राप्त उच्च पुलिस अधिकारियों को बाकायदे इसी काम के लिए नियुक्त किया था। पुलिस ने बहुत सारे छापे मारे भी, वीडियो पार्लर संचालकों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वीडियोपाइरेसी पर जब नियंत्रण नहीं हो सका, तो फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों के वीडियो राइट्स खुद-ब-खुद बेचने शुरू कर दिये।

''आज या कल उन्हें (फिल्म निर्माताओं)

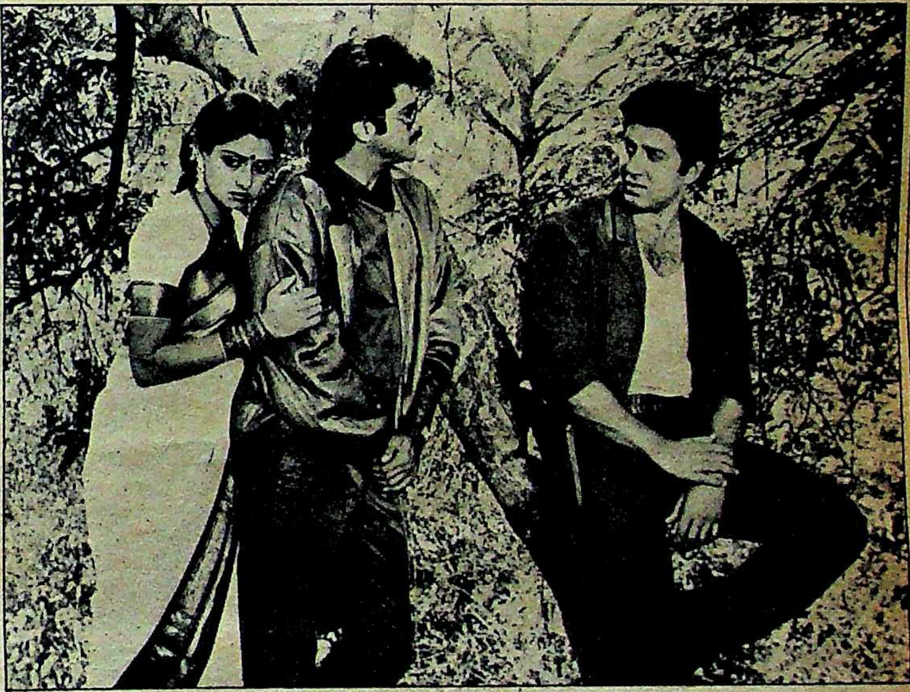

'राम औतार' में श्रीदेवी, अनिल कपूर और सनी देवल

यही रास्ता अपनाना पड़ेगा'' एक केबिल टीवी संचालक ने 'माया' को बतलाया, ''आप उस माध्यम को नहीं झुठला सकते, जो ज्यादा आरामदेह और लोकप्रिय हो रहा है। अब लोगों के पास समय कहां है कि वे सिनेमाघरों के चक्कर लगायें—पहले एडवांस बुकिंग के लिए फिर फिल्म देखने के लिए। सिनेमाघर में गुंडागर्दी तथा फिकरेबाजियों की बढ़ती घटनाओं के कारण लोग परिवार को लेकर सिनेमाघरों में जाने से कतराने लगे थे। सड़क पर बढ़ती गुंडागर्दी के कारण सिनेमाघरों के नाइट शो यों भी खाली जाने लगे थे, उस पर हर वर्ष बढ़नेवाले मनोरंजन करों के कारण टिकटों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि तथा कालाबाजारियों की योजनाबद्ध तरीके से टिकट ब्लैक में बेचने के कारण भी दर्शक सिनेमाघर जाने से हिचकने लगे, फिर सिनेमामालिक सिनेमाघरों में जरूरी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करते थे। ऐसे में आज या कल ऐसे सिनेमाघरों का टूटना अवश्यंभावी था ही। दर्शक सपरिवार दो या तीन फिल्में सिनेमाघर में देखने में जितना खर्च करते थे, अब उतनी ही राशि में वे घर बैठकर पूरे महीने तक (प्रतिदिन औसतन दो या तीन) नियमित रूप से फिल्में तथा दूसरे कार्यक्रम देख लेते हैं।''

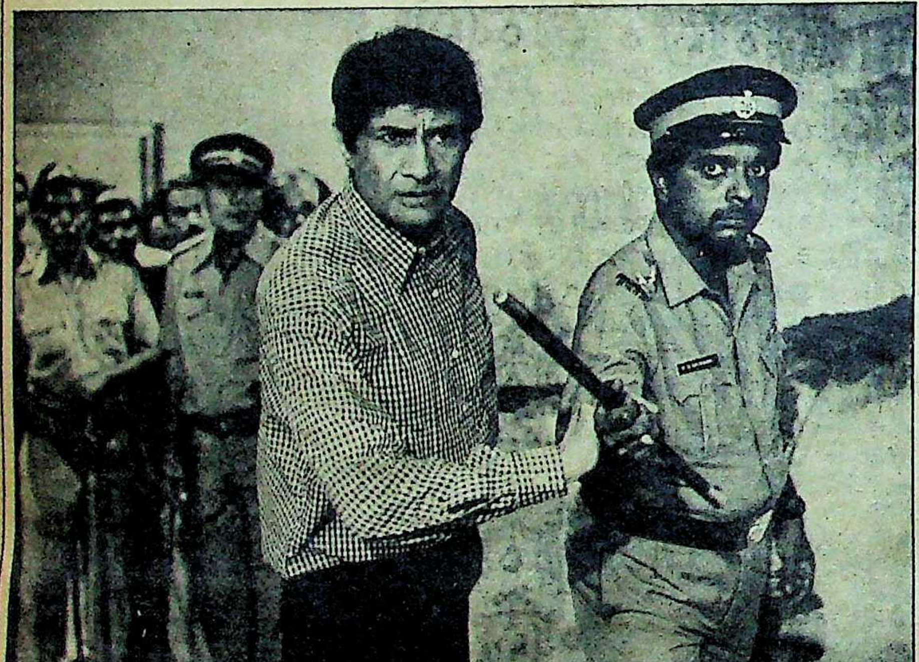

देवानंद और सदाशिव अमरापुरकर

एक दूसरे केबिल टीवी संचालक का कहना था, ''फिल्म निर्माताओं की नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन वीडियो व्यवसाय से संबंधित लोगों का केबिल टीवी के विरुद्ध उठ खड़े होने की बात अजीब-सी लगती है। दरअसल, फिल्म इंडस्ट्री को वीडियोवालों ने ही संकट में डाला था और फिल्मों के वीडियो कैसेट तमाम गलत ढंग से (फिल्म लेबोरेटरीज, सिनेमाहाल आदि से) बनवाकर वीडियो लायब्रेरियों को बेच दिये। हम तो फिल्म निर्माताओं को बाकायदे उनकी रायल्टी उसी तरह से देने के लिए तैयार हैं जैसे वितरक एवं प्रदर्शक देते हैं। फिल्म निर्माता जिस तरह से अपनी फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट वितरकों एवं वीडियो निर्माताओं को बेचते हैं, वैसे ही केबिल टीवी संचालकों को भी बेच सकते हैं। इस तरह वे अपनी आय में अतिरिक्त इजाफा कर सकते हैं। फिर आप ही बतलाइए कि केबिल टीवी से फिल्म इंडस्ट्री में संकट कैसे उत्पन्न हुआ?''

'इंफैक्ट' तथा दूसरे फिल्म एवं वीडियो निर्माता संगठनों ने केबिल टीवी के विरुद्ध एक तरह से जेहाद बोल दिया है, लेकिन केबिल टीवी संचालकों के संपर्क-सूत्र भी बड़े स्तर पर हैं। एक सूचना के अनुसार माफिया सम्राट दाऊद इब्राहीम ने भी इस धंधे में प्रवेश करने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में उसके प्रभाव तथा कानूनी पेचीदगियों के कारण फिल्म एवं वीडियो कैसेट निर्माता किस हद तक इस लड़ाई में सफल हो सकेंगे, बतला पाना कठिन है।

बहुत से केबिल टीवी संचालकों ने अत्यधिक क्षमतावाले विशालकाय डिश एंटिना लगाने की योजना तैयार की है। इससे वे पड़ोसी देशों के दूरदर्शन कार्यक्रम भी केबिल टीवी पर दिखला सकते हैं। यों भी पाकिस्तान के लोकप्रिय टीवी सीरियल केबिल टीवी पर दिखलाये जाते हैं—डिश एंटिना से वे कार्यक्रमों का सीधे प्रसारण कर सकते हैं।

''दरअसल, हम छोटे खतरे (केबिल टीवी) से डर रहे हैं'' अभिनेता-निर्माता-निर्देशक देवानंद 'माया' को बतलाते हैं, ''असली खतरा तो सैटेलाइट टीवी से है जो किसी भी समय यहां आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था दुबई से सैटेलाइट एंटिना लगाकर हिंदी या दूसरी फिल्म का प्रसारण शुरू कर दे, तो भारत में बैठकर हम भला उसका क्या कर सकते हैं? हमारा कानून उन्हें कैसे रोक पायेगा? अतएव इन वैज्ञानिक उपलब्धियों का हमें स्वागत करते हुए नये रास्ते निकालने शुरू करने चाहिए। केबिल या सैटेलाइट टीवी से हम फायदा कैसे उठायें, इसकी कारगर योजना बनाने की जरूरत है, ताकि गलत ढंग से लोग फिल्म प्रिंटों की चोरी न कर सकें। निर्माता अधिक कीमत पर अपनी फिल्मों के कापीराइट सैटेलाइट या केबिल टीवी को बेच सकते हैं। फिर सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, आखिर इसका नुकसान तो उसे भी उठाना ही पड़ेगा।''

सूचना प्रसारण मंत्रालय इस सारे मामले में खामोश है, राज्य सरकारें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं समझतीं तथा मंडी हाउस अपने आपको इस खतरे से महफूज समझता है।

''नहीं सबसे ज्यादा खतरा सरकार और दूरदर्शन को होनेवाला है,'' एक फिल्म निर्माता-वितरक ने 'माया' को बतलाया, ''जिस तरह से वीडियो कैसेट निर्माताओं ने कैसेट में उपभोक्ता-विज्ञापन भरने शुरू किये, उसी तरह केबिल टीवी वाले भी अलग से विज्ञापन, काफी कम दर पर, बटोर कर दूरदर्शन के लिए समस्या पैदा कर देंगे। राहुल रवेल ने ८० एपीसीडों का प्रथम वीडियो सीरियल 'धर्मयुद्ध' तैयार किया है। अगर वे या दूसरे सीरियल निर्माता केबिल टीवी पर अपने सीरियल प्रदर्शित करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? मंडी हाउस में तथाकथित अनियमियता, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार से क्रुद्ध बहुत से सीरियल निर्माता, प्रायोजक तथा विज्ञापनदाता केबिल टीवी और सैटेलाइट टीवी से जुड़ जायेंगे। अंततः मंडी हाउस फिल्म्स डिवीजन जैसी निरर्थक संस्था भर बनकर रह जायेगी।''

संप्रति केबिल टीवी के प्रकोप से बचने के लिए फिल्म निर्माताओं ने हालीवुड तथा जापानी फिल्म इंडस्ट्री का फार्मूला अपनाया है। एक फिल्म निर्माता ने तो टेलीफोन का तीन मंजिला सेट लगवाया, उसके ऊपर मिथुन चक्रवर्ती तथा नीलम का नृत्य फिल्माया, दूसरे निर्माता ने कमल के फूल का अतिविशालकाय सेट बनवाया जिसमें मिथुन चक्रवर्ती खिलौनानुमा दीखते हैं। उक्त निर्माता ने बतलाया, ''अब इस विशालकाय टेलीफोन सेट का आनंद आप सिर्फ बड़े परदे पर उठा सकते हैं, दूरदर्शन के छोटे परदे पर नहीं। अतएव दर्शकों को सिनेमाघर जाना ही पड़ेगा।'' फिल्म निर्माता फिलहाल 'तू डाल-डाल, हम पात-पात वाली चक्रव्यूही लड़ाई केबिल टीवी के विरुद्ध हर मोर्चे पर लड़ने के लिए उतारू हो गये हैं। लेकिन चूहे-बिल्ली के इस 'आंख-मिचौनी महाभारत' का नतीजा कोई भी आंक नहीं पा रहा है।

—रवींद्र श्रीवास्तव

नकल में असल का अहसास

खाली समय में भी बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के उद्देश्य से दुनिया में ऐसे-ऐसे खिलौने या उपकरण तैयार हो रहे हैं, जिनसे बच्चों का ज्ञानवर्धन भी होता है और मनोरंजन भी। इस क्रम में 'वीडियो गेम' काफी मुफीद साबित हुआ है। किंतु 'वीडियो गेम' में अधिकांश खेल ऐसे होते हैं, जो बच्चों की खेल-मानसिकता को संतुष्ट नहीं कर पाते। बच्चों को खुद साइकिल चलाने में जो मजा आता है, वह किसी को साइकिल चलाते देखकर उन्हें नहीं मिलता। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हर काम को प्रयोग करके जानें। बच्चों की इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए सुपर-एक्स नामक ब्रिटिश कंपनी ने 'प्रोकान' नामक १६ फुट लंबा, ६ फुट चौड़ा एक ऐसा उपकरण बनाया है, जिसमें बैठने के बाद बच्चा हवाई-यात्रा का भरपूर आनंद उठाता है। यही नहीं, वायुमंडल में स्कीइंग, घुड़सवारी, हेलीकाप्टर यात्रा, घोड़ों की दौड़ के मैदान का वास्तविक आनंद भी बच्चे को मिलता है।

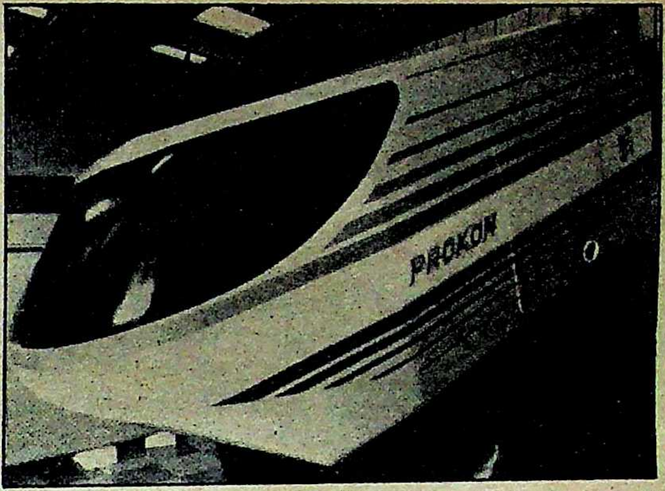

असल में, 'प्रोकान, कैप्सूलनुा एक ऐसा उपकरण है, जिसमें अधिक से अधिक चौदह बच्चे बैठ सकते हैं। 'प्रोकान' के अंदर का माहौल पूरी तरह से शांत होता है और सामने लगे एक परदे पर तरह-तरह की फिल्म दिखायी जाती है, जिसमें हवाई जहाज की यात्रा, घोड़ों की दौड़ आदि शामिल हैं। मजे की बात यह है कि जब कैप्सूल के अंदर आसमान में उड़ते हवाई जहाज का दृश्य दिखाया जाता है, तो कैप्सूल के अंदर का माहौल भी उड़ते हुए हवाई जहाज के माहौल में तब्दील हो जाता है। माहौल में जिस तेजी से परिवर्तन होता है, उसका बच्चों को अहसास भी नहीं होता और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वास्तविक हवाई जहाज में बैठकर सफर कर रहे हों।

थ्री इन वन

एटलांटा स्थित शीतल पेय कंपनी कोकाकोला ने अपने ब्रांडों को आसानी से हर जगह पहुंचाने के लिए एक नया रास्ता खोज निकाला है। इस कंपनी ने एसप्रेसो काफी मशीन की तरह ही 'ब्रेकमेट' नामक उपकरण बनाया है जो जरूरत पड़ने पर कभी भी कोकाकोला की तीनों ब्रांडों के शीतल पेय उपलब्ध करायेगा। 'ब्रेकमेट' के बाजार में आ जाने से बड़े कारखानों और कंपनियों को काफी राहत मिली है। अब बोतलों के लाने, ले जाने और उनके टूट जाने का डर समाप्त हो गया है। इस उपकरण का इस्तेमाल कंपनियों और कारखानों के अतिरिक्त बड़े सम्मेलनों, बैठकों, शादी आदि की पार्टियों में भी किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल भी मुश्किल नहीं। इस मशीन में लगे पाइप को मेनपाइप से जोड़ना पड़ता है, ताकि उपकरण में शुद्ध जल की आपूर्ति हो। उपकरण के अंदर कोकाकोला के तीनों ब्रांडों के सिरप (अर्क) मौजूद होते हैं तथा कार्बन डाईआक्साइड भी एक हिस्से में मौजूद होती है। जिसको जो ब्रांड इस्तेमाल करना हो, उसका बटन दबा दे। पलक झपकते ही नीचे रखे गिलास में मनचाहा शीतल पेय उपलब्ध हो जाता है।

Enjoy
Coke
Coca-Cola

ब्रेकमेट में उपस्थित पेयजल के 'सिरप' के खतम होने तथा कार्बन डाईआक्साइड के समाप्त होने पर नये डिब्बे खरीद कर 'ब्रेकमेट' में रखे जा सकते हैं। फिलहाल 'ब्रेकमेट' यूरोप के सभी देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि रमेश चौहान (भारतीय उद्योगपति) अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं, तो कोकाकोला पुनः भारत आ जायेगा। इस बार कोकाकोला के ब्रांड मात्र बोतलों में नहीं 'ब्रेकमेट' के जरिए भी उपलब्ध हो सकेंगे। 'ब्रेकमेट' ज्यादा महंगा भी नहीं।

दर्द हो कहां, 'एक्यूहेल्थ' हो जहां

आमतौर से लोग मामूली मोच या दर्द के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होते। कोशिश यही रहती है कि दर्द अपने आप खतम हो जाये, तो ज्यादा बेहतर है। वह तो दर्द जब पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता, तब मजबूर होकर लोग अपने डाक्टर तक जाते हैं। चीन में तो एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति पर लोगों का ऐसा विश्वास है कि मामूली-से-मामूली दर्द के निदान के लिए लोग एक्यूपंक्चर सुई का इस्तेमाल करते नहीं घबराते। शरीर के किसी भी भाग में होने वाले ऐसे दर्दों के निदान के लिए—जिनका संबंध मोच आने, नसों के कड़े हो जाने, हड्डी में मामूली चोट आने या मांसपेशियों में सख्ती आने से होता है—आस्ट्रेलिया स्थित एक्यूहेल्थ कंपनी ने एक उपकरण बनाया है, जिसका नाम है 'एक्यूहेल्थ'। इस उपकरण के आविष्कारक डाक्टर डीन रिचर्ड्स का कहना है, "एक्यूहेल्थ के इस्तेमाल से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, क्योंकि इस उपकरण में न तो कोई सुई है, जिससे त्वचा भेदी जाती हो, न ही इस उपकरण के जरिए कोई ऐसी दवा शरीर में प्रवाहित की जाती है, जिससे किसी प्रकार का नुकसान हो।" असल में इस उपकरण में ९ वोल्ट की बैटरी लगी होती है जो एक विशिष्ट प्रकार का विद्युत स्पंदन पैदा करती है। शरीर के जिस हिस्से में पीड़ा हो, बस वहां पर कुछ क्षण के लिए विद्युत स्पंदन लगाने की देर है कि पीड़ा नदारद। इसका कई बार इस्तेमाल करने से किसी तरह की भी मोंच ठीक की जा सकती है। 'एक्यूहेल्थ' पिछले कुछ महीनों से इंग्लैंड, मध्यपूर्वी देशों तथा कुछ एशियाई देशों की बाजारों में उपलब्ध हो गया है। शीघ्र ही यह उपकरण हमारे देश में भी आने वाला है।

—संयोजन: तारिक खान

शेयर बाजार की असलियत

शेयर बाजार का आकलन प्रस्तुत करने वाले विशेषज्ञ, हो सकता है, शेयर बाजार की मौजूदा बढ़त की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पुनः इस बात का ढिंढोरा पीटने लगें कि जल्दी ही शेयर बाजार का काया पलट होने वाला है, क्योंकि एक अभूतपूर्व क्रांति सन्निकट है। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि शेयर बाजार में अकसर ऐसा अस्थायी उतार-चढ़ाव आता रहता है। इससे पहले १९८६ के शुरू के छह महीनों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी थी कि लोगों को एक वास्तविक रूपांतरण का भ्रम हो गया था और हर तरफ क्रांति की बात की जा रही थी, किंतु अचानक बाजार ऐसा गिरा कि लोग सकते में आ गये।

निस्संदेह १९८६ के शुरू के छह महीनों में, १८ महीनों तक लगातार बढ़त के बाद, शेयर की जो बढ़त की प्रवृत्ति थी, उसको देखकर किसी को भी क्रांति का भ्रम हो जाना स्वाभाविक था। किंतु वह प्रवृत्ति चूंकि स्थायी नहीं थी, इसीलिए छह महीनों के बाद शेयर बाजार में जो पतझड़ आया, उसका असर ८८ के शुरू के तीन महीनों तक बना रहा। १९८८ के अप्रैल महीने से पुनः बाजार में कुछ गर्मी आयी। आज की स्थिति भी उसी गर्मी की परिणति है। यदि इसका भी गलत आकलन किया गया, तो एक बार फिर भ्रमजाल में फंसना माना जायेगा। इसमें शक नहीं कि फिलहाल शेयर बाजार अपने शबाब की ओर बढ़ रहा है, किंतु यह शबाब स्थायी भी होगा या नहीं इसका जानना बहुत जरूरी है।

फिलहाल शेयर बाजार का जो रुझान है, वह अगले दो-चार महीनों में कितना और किस गति से बढ़ेगा, इसका विश्लेषण करने के लिए शेयर बाजार की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का जायजा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौजूदा स्थिति को भुनाने के लिए सट्टा-बाजार में बैठे लोग तरह-तरह का भ्रम पैदा कर सकते हैं तथा पुनः क्रांति का भ्रम फैल सकता है। नतीजतन छोटे और मध्यम वर्ग के बचत के अभिलाषी लोग पुनः अपने शेयरों के प्रार्थनापत्र जमा करने की उत्सुकता के साथ बैंकों में लाइन में खड़े होने का कष्ट झेलने को तैयार हो जायेंगे, क्योंकि शेयर बाजार की मौजूदा बढ़त की प्रवृत्ति शेयर बाजार के शबाब के दिनों का धोखा पैदा कर सकती है।

वित्तमंत्री चह्वाण

जब बचत कर सकने की क्षमता रखने वाले परिवारों का मात्र ११ से १२ प्रतिशत भाग ही शेयर-व्यापार में रुचि रखता है, तो क्रांति की बात किस आधार पर सोची जाये?

इसमें संदेह नहीं कि फिलहाल शेयरों की कीमत लगातार तेजी से बढ़ रही है। 'इकानामिक टाइम्स' का बंबई का सूचकांक एक जुलाई के ३०७.१ की अपेक्षा अक्तूबर के शुरू में ३९६.७ पर पहुंच गया था। किंतु यदि माहवारी औसत को ध्यान में रखा जाये, तो दिसंबर में संख्या ३७३.६ ही रहेगी। यही नहीं, सभी बाजारों के सूचकांकों में एक महीने में १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बंबई को छोड़कर कुछ बाजारों में तो दुगनी वृद्धि भी नजर आयी है। कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमत तो दुगने से भी ज्यादा बढ़ी। सूचकांक की मौजूदा बढ़त से यह बात भी साफ हो गयी कि शेयरों की कीमतें तभी बढ़ती हैं, जब यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआई) किसी कंपनी के शेयर बड़ी संख्या में खरीद लेता है। जब यूटीआई शेयरों की खरीद नहीं करता, तो कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि बाजारों को बढ़त की प्रवृत्ति प्रदान करना वित्तीय संस्थाओं (जैसे यूटीआई आदि) के हाथ में है। उन्हीं की खरीद-फरोख्त से शेयर बाजार की नर्मी और गर्मी निर्धारित होती है।

शेयर बाजार के शबाब के वर्ष (१९८६) में व्यापार का आय-व्यय तथा खरीद-फरोख्त का मूल्य १३६०० करोड़ रुपए था और पिछले साल यह गिरकर ८७४० करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मौजूदा चढ़ाव का आकलन करनेवाले विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में आय-व्यय तथा खरीद-फरोख्त का मूल्य १८,००० करोड़ रुपए तक पहुंच जायेगा। इन संकेतों से तो यही लगता है कि बाजार की बढ़त यों ही जारी रहेगी तथा फिलहाल बाजार में कूदनेवाले शेयरों की खरीद-फरोख्त से भारी लाभ उगाह लेंगे। इतना जरूर है कि लाभ तभी तक जारी रहेगा, जब तक खरीद-फरोख्त का बाजार गर्म रहेगा।

धोखे की आशंका: यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि कभी-कभी बाजार का रुझान देखकर निर्णय करने में धोखे का सामना करना पड़ता है। यह खतरा शेयर बाजार में तो सदा ही बना रहता है। इसलिए उन कारणों का जायजा लेना अत्यंत जरूरी है जो शेयर बाजार में इस तरह की प्रवृत्ति के जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो किसी बाजार में प्रतिदिन अथवा प्रतिसप्ताह या प्रतिमाह अथवा प्रतिवर्ष की खरीद-फरोख्त का ब्यौरा सामने रखना बहुत जरूरी है। इस बात का महत्व उन बाजारों में ज्यादा होता है, जहां पुराने शेयरों की खरीद-फरोख्त होती है, क्योंकि जिन बाजारों में शेयरों की सीधी खरीद-फरोख्त होती है, वहां खरीद-फरोख्त का ब्यौरा हासिल करना मुश्किल नहीं होता।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है शेयर की कीमतों की बढ़त का जायजा लेना। ऐसे बाजारों में जहां शेयरों की खरीदारी या बिक्री सीधे नहीं होती, खरीद-फरोख्त का मूल्य दो वजहों से प्रभावित होता है: एक तो बड़ी मात्रा में शेयरों के लेन-देन से तथा दूसरे शेयरों की कीमतों में वृद्धि से। असल में होता यह है कि जब किसी कंपनी के नये शेयरों की घोषणा होती है, तो आम ग्राहक वे शेयर तभी खरीदता है, जब देख लेता है कि उन शेयरों का बाजार में अच्छा लेन-देन है। ऐसी स्थिति में वह सीधे शेयर नहीं खरीद पाता और उसे उन बाजारों में व्यापार करने पर बाध्य होना पड़ता है, जहां खरीदे गये शेयर पुनः बेचे जाते हैं।

इसीलिए ऐसे बाजारों को विश्लेषण का प्रमुख केंद्र बनाना जरूरी है, जहां कंपनियों द्वारा बेचे गये शेयरों की बिक्री होती है तथा खरीदारी की जाती है। इन बाजारों का करीब से सर्वेक्षण करने से उन कारणों का पता चल सकता है जो शेयर बाजार की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। इन बाजारों से कीमतों के बढ़ने या घटने की दरें, खरीद-फरोख्त में लगे रुपयों की मात्रा तथा इस खरीद-फरोख्त में जूझ रहे लोगों की संख्या आदि का ब्यौरा यदि हासिल कर लिया जाये, तो बाजार के रुझान के स्थायित्व का अंदाज लगाया जा सकता है। किंतु अफसोस इस बात का है कि इन बाजारों में जूझ रहे लोगों की संख्या का ब्यौरा हासिल कर पाना संभव नहीं है।

शेयरधारकों की संख्या: अब आइये सबसे पहले यह जानने की कोशिश की जाये कि किसी एक कंपनी का कम से कम एक शेयर खरीदने वालों की तादाद क्या है? हालांकि संतोषजनक आंकड़े मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, फिर भी अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। यह बात सर्वविदित है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास सबसे ज्यादा शेयर धारक हैं। कुछ समय पूर्व रिलायंस के शेयरधारकों की संख्या लगभग १७ लाख बतायी गयी थी। यदि उसकी अन्य कंपनियों के नये धारकों को भी शामिल कर लिया जाये, तो शेयरधारकों की संख्या (अप्रवासी धारकों को छोड़कर) २० लाख तक पहुंच जायेगी।

इसी तरह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) को दूसरी सबसे ज्यादा शेयरधारकों वाली कंपनी कहलाने का गर्व प्राप्त है। इसी श्रृंखला में बिड़ला समूह की कुछ कंपनियां भी शामिल की

जाती हैं। २० अन्य महत्त्वपूर्ण कंपनियां हैं, जिनके शेयर बाजारों में चर्चा के विषय बने रहते हैं। लेकिन इन सभी कंपनियों के पास कुल ४० लाख शेयरधारकों से अधिक शेयरधारक नहीं होंगे। इस ४० लाख की संख्या में भी ३० से ४० प्रतिशत ऐसे धारक मिल जायेंगे जो एक से अधिक कंपनी के शेयरधारक होंगे। कम-से-कम एक शेयर रखने वाले लोगों की संख्या २४ से २७ लाख के बीच ही निकलेगी। यहां पर यह बताना जरूरी है कि २४ से २७ लाख शेयरधारकों का अर्थ २४ से २७ लाख परिवार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि एक ही परिवार के कई सदस्य अलग-अलग पते देकर ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने का प्रयत्न करते हैं। यदि उन परिवारों की संख्या कुल शेयर धारकों का १० प्रतिशत मान ली जाये, जहां एक ही परिवार में एक से अधिक शेयर धारक हैं, तो कुल शेयरधारक परिवारों की संख्या २२ से २४ लाख के बीच निकलेगी।

अब शेयरधारकों के निवास के अनुसार संख्याओं का ब्यौरा हासिल करना है। कितने शेयर धारक छोटे नगरों में रहते हैं, कितने महानगरों के निवासी हैं तथा कितने गांवों में जीवनयापन कर रहे हैं? यह माना गया है कि गांवों के शेयरधारकों की अधिकतम संख्या कुल शेयरधारकों की संख्या का ८ प्रतिशत है, यानी कुल संख्या का बारहवां भाग। यह संख्या लगभग दो लाख के बराबर है। नगरों में ४०० लाख शेयरधारक परिवारों में २० लाख शेयरधारक हैं। यानी परिवारों की संख्या का ५ प्रतिशत। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में १० करोड़ लोग—२ करोड़ परिवार—ऐसे हैं, जिनकी हैसियत कीमती साजोसामान खरीदने की है। इसी संख्या का एक बड़ा भाग बचत करने में सक्षम है। किंतु असलियत यह है कि इस बचत कर सकने वाली संख्या का मात्र ११ से १२ प्रतिशत भाग ही शेयर खरीदना पसंद करता है या इस तरह से बचत करने के पक्ष में है।

क्रांति की संभावना नहीं : क्या इस स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हमारे देश के शेयर बाजार का कायापलट या उसमें क्रांति की संभावना है? जब बचत कर सकने की क्षमता रखने वाले परिवारों का मात्र ११ से १२ प्रतिशत भाग ही शेयर-व्यापार में रुचि रखता है, तो क्रांति की बात किस आधार पर सोची जाये? यदि इस बात का जायजा लिया जाये कि कितने लोग शेयर-बाजार का उतार-चढ़ाव जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो संख्या देखकर क्रांति की संभावना का सपना पूरी तरह से बिखर जायेगा।

खैर क्रांति हो या न हो, इस तथ्य से नहीं इनकार किया जा सकता कि कई लाख नये लोगों ने ८६-८७ में शेयर-व्यापार में प्रवेश लिया था। सभी को यह उम्मीद थी कि इस व्यापार में वे तेजी से रुपए कमा लेंगे, क्योंकि बैंकों द्वारा दिये जानेवाले ब्याज से शेयर में फायदा ज्यादा था। इससे ज्यादा वे इस बात से आश्वस्त थे कि जिस तरह से कीमतों में बढ़त चल रही है, उससे तो काफी लाभ कमाया जा सकता है। उस समय तो हालत यह हो गयी थी कि विशेषज्ञों ने नये लोगों के प्रवेश को 'शेयरबाजार संस्कृति में फैलाव' माना था। किंतु सच तो यह है कि संस्कृति का यह फैलाव समयबद्ध था। जब शेयर की कीमतें गिरने लगीं, तो लोगों का इस संस्कृति के प्रति लगाव अपने आप समाप्त होने लगा। जाहिर है, इस लगाव को स्थायी तभी बनाया जा सकता है जब लाभ निरंतर होता रहे और शेयर खरीदने के लिए पैसों की कमी महसूस न हो। स्थिति यह हो गयी थी कि बैंक अपने व्यापार को लेकर चिंतित होने लगे थे, क्योंकि उनके यहां बचत करनेवाला समाज का एक बड़ा भाग शेयर-बाजारों की ओर भाग रहा था। शेयर-बाजार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि छोटे दुकानदारों, वकीलों, डाक्टरों, अभियंताओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, यहां तक कि टैक्सीचालकों ने शेयर खरीदने में रुचि दिखायी थी।

अब सवाल यह है कि क्या ८६-८७ के सबक से उनकी आंखें खुली नहीं हैं? क्या बाजार पुनः उन सीमित आयवाले नये धारकों को विश्वास दिला सकेगा? कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है। एक बार शेयर बाजार की चमक-दमक का अंदाज उन्हें हो चुका है, वे जानबूझकर अपने आपको ऐसे व्यापार में नहीं शामिल करेंगे, जहां पलक झपकते ही सब कुछ चले जाने का खतरा सदा बना रहता है। अब तो उन्हें कोई यह भी नहीं समझा सकता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह की नामीगिरामी कंपनियों के शेयर खरीदने में किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता, क्योंकि सचाई यही है कि शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई भरोसा नहीं। जाहिर है, जिन लोगों ने शेयर बाजार में क्रांति की संभावना की चर्चा सुनकर धोखा खाया है, वे काफी सतर्क हो गये हैं। वे पुनः अपनी मेहनत की कमायी खतरे में नहीं डालेंगे। वे अब शेयर बाजार की ओर तभी आकर्षित होंगे, जब उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो जायेगा कि इस बार उनका पैसा डूबने वाला नहीं। ऐसी स्थिति तभी बन सकती है जब मौजूदा बढ़त की प्रवृत्ति स्थायी हो जाये और लंबे समय तक कायम रहे। किंतु क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसे अपनाने से शेयर बाजार की बढ़त की प्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान किया जा सके? इसके लिए जरूरी है कि औद्योगिक उत्पादन में बहुमुखी वृद्धि होती रहे, कंपनियों का मुनाफा निरंतर बढ़ता रहे और सरकार कंपनियों को और शेयरधारकों को निरंतर सुविधाएं देती रहे तथा शेयरबाजारों में धन लगाने वालों का तांता बंधा रहे। किंतु सवाल यह है कि क्या यह सब स्थायी रूप धारण कर सकता है? यदि नहीं, तो फिर शेयरबाजार के रुख में स्थायित्व कैसे लाया जा सकता है? कंपनियों का मुनाफा समय-समय पर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सरकार सुविधाएं जारी भी रख सकती है और बंद भी कर सकती है। इसलिए बाजार की प्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान करने का कोई रास्ता नहीं दिखायी देता। हां, एक उम्मीद जरूर है। इस वर्ष ३० से ४० लाख टन अतिरिक्त अनाज उपलब्ध रहेगा। इस अतिरिक्त आय से किसान वर्ग महंगी वस्तुएं खरीद सकता है, जिससे कंपनियों के उत्पादन की बिक्री बढ़ेगी तथा कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे। किंतु यह फायदा भी कुछ गिनी-चुनी कंपनियों को ही पहुंचेगा, क्योंकि किसान वर्ग वही सामान खरीदेगा, जिसकी उसे जरूरत है। यह भी संभावना है कि हो सकता है इस वर्ष चुनाव का खयाल करते हुए सरकार कुछ रियायतों की घोषणा कर दे और कंपनियों को कुछ फायदा हो जाये। वे कंपनियां, जिनकी बाजार में फिलहाल धाक है, मुश्किल से ७०-७५ होंगी। संभव है उनके शेयरों की कीमत कुछ बेहतर बनी रहे। किंतु मात्र इतने से ही रूपांतरण या क्रांति की बात सोचना अनुचित तो कहलायेगा ही।

क्या बाजार पुनः उन सीमित आयवाले नये धारकों को विश्वास दिला सकेगा। कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है। एक बार शेयर बाजार की चमक-दमक का अंदाज उन्हें हो चुका है, वे जानबूझकर अपने आपको ऐसे व्यापार में नहीं शामिल करेंगे, पलक झपकते ही सब कुछ चले जाने का खतरा सदा बना रहता है।

फिलहाल बाजार में जिस गरमी का अहसास हो रहा है, वह चंद कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं या शेयर दलालों की बदौलत ही है। कुछ धनवान लोग तो हमेशा ही कुछ कंपनियों के शेयर अधिक से अधिक मात्रा में खरीदने की टोह में रहते हैं। शेयर ही एक ऐसा रास्ता है, जिसके जरिए धनवान अपनी श्रेणी के लोगों पर अपना वर्चस्व जमा पाते हैं। इसी तरह वित्तीय संस्थाएं, जैसे यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, जीवन बीमा निगम आदि, भी ऐसे मौकों पर शेयर खरीद लेती हैं, जब शेयर की कीमतों के घटने का अंदेशा होता है। ऐसा करके वे शेयर बाजार के अस्तित्व की सुरक्षा करती हैं। इनके द्वारा बड़ी मात्रा में शेयर खरीद लिए जाने से कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, जिससे शेयर बाजार में आनेवाले बदलाव का भ्रम पैदा होता है और लोग शेयर बाजारों की ओर आकर्षित होते हैं। कभी-कभी शेयर बाजारों में बैठे दलाल भी ऊंची दरों पर शेयर खरीदकर इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि बाजार बढ़त की ओर अग्रसर है। किंतु इस तरह के लेन-देन दलाल आपस में ही करते हैं।

इसलिए ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में पैदा होनेवाली गरमी का भ्रम तो फैलाया जा सकता है, किंतु बाजार की प्रवृत्ति को स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता।

—कुमारेश चक्रवर्ती

When you are searching Your interest areas in an English magazine....

....Take a look at PROBE INDIA

PROBE
An Appeal to You
ANTULAY Splitting the Cong
REKHA "I still need romance"
Indian ... Pak Women ... by ... Abbas & Uma Vasudev
EXCLUSIVE FROM THE SOUTH
Reddy Report on Sexuality in Madras
Battle of the ...

If business, investment climate and the share market are the areas of your interest, Probe has some of the most investigated reports on the contemporary scene to share with you.

If it is the political scene, you will be more than satisfied with the objective reports from all around the country.

There is almost everything in Probe, you could look for–sports, cinema, media, focus on international scene, women, lifestyle, human interest and regional coverages.

And for your leisure you have the visual delight of photo-features.

Probe is an interesting and bold blend of topical coverage with an insight into the future, for we take a stand on controversial issues.

PROBE
INDIA
Reporting with credibility that's seeded within.

एक रुपया १२ पैसे के बराबर

रुपए का क्या मूल्य है? हर महीने रुपए का क्रय मूल्य गिरता जा रहा है। अब वह १२ पैसे या २ आने बराबर रह गया है। एक वर्ष पूर्व वह १३.३३ पैसे और उसके एक वर्ष पहले यह १४.६० पैसे था।

गोकि सरकार दावा करती है कि उसने मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया है, किंतु कीमतें अलग कहानी कहती हैं। गत तीन वर्षों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १० प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ता रहा है। यह इसके पूर्व के दस वर्षों की मुद्रास्फीति से ५० प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार हर तीन वर्ष में रुपए के मूल्य का २५ प्रतिशत घट जाता है। इस दर से अगले ५-६ वर्षों में इसका मूल्य ६ पैसे या एक आना रह जायेगा।

रुपए की विदेशी बाजारों में भी यही स्थिति है। उसका गत ८ वर्षों में अधिकांश विदेशी मुद्राओं व खासकर डालर की तुलना में ५० प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है। पांच वर्ष पूर्व आप एक पाउंड स्टर्लिंग १५ रुपए में खरीद सकते थे। अब उसके लिए आपको २८ रुपए देने पड़ेंगे। जानकारों का कहना है कि ऐसी सूरत में १९९४ में आपको एक पाउंड के बदले में लगभग ५० रुपए व शताब्दी के अंत तक १०० रुपए अदा करने पड़ेंगे।

निरमा से टक्कर

लिज्जत पापड़ को घर-घर में लोकप्रिय बनाने वाली महिला उद्योग सहकारिता की रुक्मिणी बेन पवार आज लिज्जत पापड़ के लिए वही छलांग भरने में रत हैं, जैसी निरमा ने कुछ वर्ष पूर्व भरी थी—अर्थात डिटर्जेंट के उत्पादन व विक्रय व्यवसाय में प्रवेश। उसने (महिला-उद्योग ने) डिटर्जेंट साबुन 'सासा' बनाकर बाजार में प्रवेश किया है, जिसकी कीमत निरमा से थोड़ी कम है।

'सासा' को हिंदुस्तान लीवर व गोदरेज—जो निरमा से संत्रस्त होकर बाजार में नये जोशोखरोश से उतरे हैं—से कड़ी प्रतिद्वंद्विता करनी पड़ेगी। किंतु 'सासा' को शायद कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पहले से ३० हजार से ज्यादा ग्राहक (महिलाएं) हैं जो अपने घरों में पापड़ बनाकर बिक्री के लिए महिला उद्योग को देती हैं। इस नये व्यवसाय से उनकी सूची में लगभग ४ हजार श्रमिक और जुड़ जायेंगे जो निस्संदेह 'सासा' के खरीदार बनेंगे।

'सासा' को हिंदुस्तान लीवर व गोदरेज—जो निरमा से संत्रस्त होकर बाजार में नये जोशोखरोश से उतरे हैं—से कड़ी प्रतिद्वंद्विता करनी पड़ेगी। किंतु 'सासा' को शायद कोई खास दिक्कत नहीं होगी।

उधर डिटर्जेंट बाजार में तहलका मचाने वाला निरमा नये क्षेत्र में कदम रख रहा है। वह ४०० करोड़ की लागत वाली फैक्ट्री लगा रहा है। फैक्ट्री ऐसे जिंसों का उत्पादन करेगी, जिसे डिटर्जेंट निर्माता इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, उसे जबर्दस्त टक्कर लेनी होगी, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी हिंदुस्तान लीवर है।

सट्टा बाजार का उछाल

सट्टा बाजार का हाल निराला है। जब हरेक यह कह रहा था कि बाजार में उछाल आयेगा, तभी उसमें मंदी का रुख आया। इस बारे में भी अफवाह है कि क्यों उसके दमखम में कमी आयी है। सट्टा बाजार में सहसा ५० प्रतिशत का जो उछाल आया था, वह कमोबेश बरकरार है। किंतु जिन लोगों की भविष्यवाणी थी कि इसमें ५० प्रतिशत की और बढ़ोतरी होगी, वह सही साबित नहीं हुई।

इसका पहला कारण यह है कि बाजार में सहसा उछाल आने के बाद स्थिति राहत की सांस लेने जैसी है। दूसरे, यह बजट-पूर्व समय है, जब कोई भी बात हो सकती है। अफवाह है कि वित्त मंत्री एसबी चह्वाण का संभवतः अन्य मंत्रालय में तबादला हो रहा है और ऐसी बातों से बाजार का डांवांडोल होना स्वाभाविक है।

फौरी चुनाव की भी अफवाहें हैं। अधिकांश लोगों का मानना था कि तमिलनाडु में शासक दल की फतह या बेहतर भूमिका सरकार को फौरी चुनावों के लिए प्रेरित कर सकती है। अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस यदि वहां हार भी जाती है या उसकी भूमिका निराशाजनक होती है, तो भी यह मौका फौरी चुनावों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि विपक्ष बंटा हुआ है। उसे (विपक्ष को) अधिक समय देना और अपने को एकजुट करना होगा। इनमें से किस अफवाह को गंभीरतापूर्वक लिया जाये, यह कोई नहीं जानता। ऐसी हालत में सट्टा बाजार में निरंतर गिरावट संभव नहीं।

सट्टा बाजार में सहसा ५० प्रतिशत का जो उछाल आया था, वे कमोबेश बरकरार है। किंतु जिन लोगों की भविष्यवाणी थी कि इसमें ५० प्रतिशत की और बढ़ोतरी होगी, वह सही साबित नहीं हुई।

टाटा घराने की सक्रियता

टाटा को छोड़कर परिवार आधारित लगभग तमाम भारतीय व्यावसायिक घराने विभाजित हो रहे हैं। जहां अन्य व्यावसायिक घराने बंटते जा रहे हैं, वहीं टाटा घराना जेआरडी व उनके परिवार की ही छत्रछाया में फलफूल रहा है। महज तीन सक्रिय टाटा हैं। जेआरडी, उनके चचेरे भाई नवल टाटा और नवल के पुत्र रतन टाटा। रतन हाल में सुमंत मुलगांवकर के स्थान पर समूह की दूसरी सबसे बड़ी इकाई टाटा इंजीनियरिंग के चेयरमैन बने हैं।

किंतु विशाल टाटा व्यावसायिक समूह के पेंच में पेंच है। मसलन दरबारी सेठ का अपना एक लघु समूह भी उससे जुड़ा है। दरबारी सेठ वर्षों से टाटा कैमिकल्स के कर्ताधर्ता रहे हैं। वे चार प्रमुख कंपनियों—टाटा कैमिकल्स, टाटा फर्टिलाइजर्स, टाटा टी और रैलिस के चेयरमैन हैं। एक अन्य कंपनी—एसोसिएटेड सीमेंट—जिसका हाल में अधिग्रहण किया गया है—तो बिलकुल उनके अधिकार क्षेत्र में है। इस लघु समूह का सालाना कारोबार १५०० करोड़ रुपए है तथा कर पूर्व मुनाफा ७५ करोड़ है। यह स्वयं में एक व्यावसायिक घराना है। वैसे ७० वर्षीय सेठ को ऐसा कोई गुमान नहीं है।

पेट्रोकैमिकल्स का आकर्षण

हर व्यावसायिक घराना आज पेट्रोकैमिकल्स के पीछे पड़ा है। पहले निजी क्षेत्र में मात्र एक पेट्रो कांप्लेक्स—यूनियन कार्बाइड था, किंतु अब अनेक हैं। मसलन रिलायंस का हजीरा स्थित संयंत्र। इसके अलावा विजय मलैया के युनाइटेड ग्रुप की आंध्र प्रदेश में एक इकाई है। लुधियाना के अभय ओसवाल ने चैंबूर (बंबई) स्थित यूनियन कार्बाइड को खरीद लिया है और उसे नये व्यापक संयंत्र में बदलने जा रहे हैं। यह भी खबर है कि हल्दिया को खरीदने के लिए वर्षों दौड़-धूप करने वाले आरपी गोयनका तमिलनाडु में १००० करोड़ रुपए की 'पेट्रोकैमिकल्स इकाई' स्थापित कर रहे हैं। मफतलाल भी पुणे के सागर तट पर एक इकाई लगाने के चक्कर में हैं। टाटा भी इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए सक्रिय हैं। सरकार भी नैफ्था और एलपीजी का आयात कर रही है और शायद उसकी भी अपनी कोई योजना है। इस व्यवसाय में भारी मुनाफा है तभी तो हरेक भागदौड़ कर रहा है।

—डा० जय दुबाशी

नवजोत सिंह सिद्धू

हत्या का आरोप

ऐसी कौन-सी वजहें हैं कि क्रिकेट के उदीयमान खिलाड़ी सिद्धू पर पटियाला के एक परिवहन व्यवसायी की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। क्या इस आरोप से उनके भावी खेल जीवन पर प्रश्नचिह्न लग जायेगा?

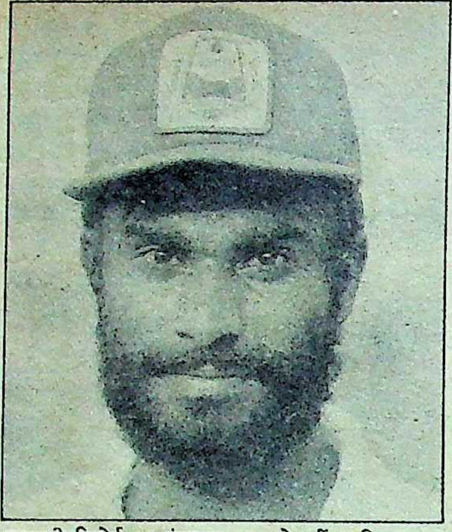

डाक्टरी रिपोर्ट का इंतजार: नवजोत सिंह सिद्धू

जाहिर है, इस बार के वेस्टइंडीज दौरे में वह जान नहीं होगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू हत्या के आरोप से जूझने में व्यस्त हैं। २७ दिसंबर '८८ को जसविंदर सिंह द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में सिद्धू पर पटियाला के परिवहन व्यवसायी गुरनाम सिंह की हत्या का आरोप लगाया गया है। हत्या के आरोप में फंसाये जाने की खबर पाते ही सिद्धू ने फरार होना बेहतर समझा, ताकि पुलिस के शिकंजे से बाहर रह कर अपनी बेगुनाही साबित करने के साधन जुटा सकें। जाहिर है, जिस व्यक्ति ने कत्ल करना तो दूर कभी कत्ल के बारे में सोचा भी न हो, उस पर यदि अचानक इस तरह का आरोप लगाया जाये, तो वह बौखला ही जायेगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव रणबीर सिंह का कहना है, "सिद्धू के शानदार प्रदर्शनों को मद्देनजर रखते हुए यह तय था कि उसे वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुन लिया जाता, किंतु बेचारा बेवजह हत्या के आरोप में फंसाया जा रहा है।" इसी तरह सिद्धू का पक्ष लेते हुए भूतपूर्व खिलाड़ी योगराज सिंह बताते हैं, "मैं शेरी (सिद्धू का उपनाम) को चार वर्ष की उम्र से देख रहा हूं। अपनी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्ति की हत्या करना तो बड़ी बात हुई सिद्धू जानवरों के शिकार का भी पक्षधर नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस तरह के काम से सिद्धू का कोई संबंध नहीं।" सिद्धू के बारे में बताते हुए योगराज सिंह कहते हैं कि उन्हें याद है वह दिन जब सिद्धू उनके साथ शिकार पर गये थे। वहां उन्होंने एक तीतर मारी थी जिस दृश्य को सिद्धू सहन नहीं कर सके थे और उसी सदमे में एक साल तक मांस न खाने की कसम खा बैठे थे। जिस व्यक्ति का हृदय इतना कोमल हो वह किसी व्यक्ति की हत्या कर देगा ऐसा लगता नहीं। सिद्धू के खिलाड़ी दोस्तों का भी यही ख्याल है। उनका तो कहना है, "हमारा सिद्धू ऐसा कर ही नहीं सकता।" क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि इसे भाग्य का ही खेल माना जायेगा कि सिद्धू जैसा खिलाड़ी हत्या के आरोप में फंसाया जा रहा है। फिर भी ऐसा नहीं है कि बिना कुछ हुए ही सिद्धू इस तरह के आरोप के शिकार हुए हैं। लोगों का बताना है कि कुछ दिन पूर्व शेरावाला गेट चौक पर जब सिद्धू अपने मित्र के साथ मारुति में बैठे जा रहे थे, तो पीछे से आ रही गाड़ी के चालक (गुरनाम सिंह) द्वारा ओवर टेक करने में कुछ किच-किच हो गयी थी और मारपीट की नौबत आ गयी थी। उसी हादसे का यह नतीजा था कि जब गुरनाम सिंह की किसी ने हत्या कर दी, तो सिद्धू से हुई किच-किच को मद्देनजर रखते हुए सिद्धू पर ही कत्ल का इलज़ाम लगाया गया।

असलियत क्या है?: शेरावाला चौक के करीब बैठनेवाला एक पान वाला मुन्ना इस संबंध में बताता है, "इस चौराहे पर दिन भर अफरातफरी मची रहती है। यह शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है। परंतु यहां यातायात को नियंत्रण में रखने के लिए जो बत्तियां लगी हैं, वे ठीक तरह से काम न करने की वजह से अव्यवस्था और बढ़ाती हैं। २७ दिसंबर को करीब सवा बारह बजे सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह के साथ अपनी मारुति जिप्सी में माल रोड की तरफ जा रहे थे। लाल बत्ती देखकर वे लोग शेरावाला गेट चौराहे पर रुके। चूंकि लाल बत्ती अकसर बहुत देर तक जलती रह जाती है इसलिए जल्दी से आगे निकलने की चाह के कारण अकसर कार चालकों में तू-तू मैं-मैं होती है। उस दिन भी सिद्धू की जिप्सी के पीछे से आ रही मारुति के ड्राइवर ने पीछे से हार्न दिया और सिद्धू से आगे बढ़ने को कहा। गाड़ी चला रहे रूपिंदर ने मारुति चालक से ठहरने को कहा।"

आगे का हादसा बयान करते हुए सिद्धू बताते हैं, "तब मारुति ने हमें ओवरटेक किया और हमारे आगे आकर खड़ी हो गयी। गुरनाम हमें गालियां देने लगा और अपनी कार से निकल कर रूपिंदर से भिड़ गया। कार में बैठे अन्य लोगों ने, जो मजदूर लग रहे थे, मुझ पर हमला करना चाहा। चौराहे के आसपास के लोगों के लिए यह कोई नयी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे झगड़े आये दिन होते ही रहते हैं। इत्तफाक से चौराहे पर एकत्र हुई भीड़ ने मुझे पहचान लिया और लोग मुझे घेरे में लेकर खड़े हो गये। कुछ लोगों ने गुरनाम सिंह वगैरह से 'सब कुछ भुलाकर' चले जाने को कहा। मैंने भी लोगों की बात मान ली और झगड़े को बेवजह बढ़ाने के बजाय मैं दोस्त के साथ बैठकर आगे चला गया।"

गलतबयानी का आरोप: किंतु गुरनाम सिंह के परिवार के एक सदस्य का कहना है कि सिद्धू गलतबयानी कर रहे हैं। सचाई तो यह है कि सिद्धू गुरनाम सिंह को मारकर वहां से भागे थे। प्राथमिकी दर्ज कराने वाले जसविंदर सिंह के अनुसार सिद्धू ने उनके चाचा को घूंसा मारा था। जिससे उनकी जान चली गयी। उनका यह भी दावा है कि भागने से पहले सिद्धू मारुति कार की चाबी भी लेते गये थे।

हादसे के बाद सिद्धू लौटकर घर पहुंचे। उस दिन उनकी शादी की वर्षगाठ थी। वे अपनी पत्नी डा० नवजोत कौर और पांच महीने की बिटिया के साथ अपने गांव मानवाला में थे जब उन्होंने ८.४० का दूरदर्शन का समाचार सुना। इसी में यह समाचार भी था कि गुरनाम सिंह की सिद्धू ने हत्या कर दी है। खबर सुनते ही सिद्धू हरकत में आ गये थे।

गुरनाम के परिवारजनों और दोस्तों द्वारा बदले की कार्रवाई तथा पुलिस के हाथों परेशान होने से बचने के लिए सिद्धू छुप गये। वे पटियाला और चंडीगढ़ में अपने दोस्तों के यहां छुपे रहे। इसी बीच पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर के खिलाफ धारा ३०४/३४ के तहत मामला दर्ज कर लिया।

नवजोत सिद्धू अपनी सफाई पेश करते हुए तो यही बताते हैं कि उनका गुरनाम सिंह के कत्ल से दूर का भी संबंध नहीं। किंतु शेरावाले चौक के हादसे के बाद हुई गुरनाम सिंह की हत्या सिद्धू पर कत्ल का इलजाम लगाने के लिए काफी तो है ही। यदि गुरनाम सिंह की हत्या का राज नहीं खुलता, तो सिद्धू पर आरोप बना रहेगा और यह साबित करना मुश्किल होगा कि गुरनाम सिंह का कत्ल सिद्धू ने नहीं किया। इतना जरूर है कि डाक्टरी जांच की रिपोर्ट आने पर असलियत का कुछ पता चल सकेगा। मृतक की बायीं कनपटी पर जो निशान था वह किसी हथियार के वार का भी हो सकता है। लेकिन प्राथमिकी में 'मुक्का मारने' की बात कही गयी है। यदि 'मुक्का' मारने की बात गलत साबित हो जाती है, तो सिद्धू को कुछ राहत जरूर मिलेगी, किंतु फिर भी उन पर आरोप तो बना ही रहेगा। यह भी कहा जा रहा है कि गुरनाम सिंह को दिल की तकलीफ थी, इसलिए उस वक्त दिल का दौरा पड़ने से भी उसकी मौत हो सकती है। अब तो सारा दारोमदार डाक्टरी रिपोर्ट पर ही है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस तरह की अफवाहें फैलती रहेंगी और सिद्धू का भविष्य अधर में लटका रहेगा।

—विवेक शर्मा, पटियाला से लौटकर

सचिन तेंदुलकर

कम उम्र, पर लम्बी पारी

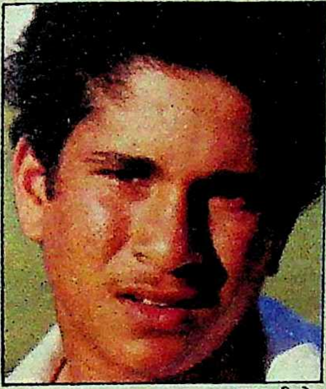

छाया: बिमोर

१६८६ में जूनियर क्रिकेट मैच के दौरान १३ वर्षीय सचिन तेंदुलकर ने अपने खेल का जो अभूतपूर्व प्रदर्शन किया उसे देखकर लोग भौंचक्के रह गये। जाहिर है क्रिकेट की दुनिया में एक स्कूली बच्चे द्वारा प्रवेश करते ही ३२६ रन बनाकर नाबाद (नाट आउट) रहना और बायें हाथ के बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ ६६४ रनों की विश्व रेकार्ड साझेदारी पेश करना कोई मामूली बात तो है नहीं। बस फिर क्या था समाचार-पत्रों ने सचिन को सुर्खियों में बिठा दिया। हर तरफ सचिन का ही गुणगान था। क्रिकेट प्रेमियों तथा खेल के दिग्गजों ने इस उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी में गुण-दोष ढूंढ़ने शुरू किये और इस नतीजे पर पहुंच गये कि सचिन भले ही क्रिकेट जगत में फिलहाल प्रवेशार्थी की हैसियत से जाना जाता है, किंतु उसके खेल में सुनील गावस्कर की 'स्टाइल' साफ दिखायी देती है। यही नहीं, सचाई तो यह है कि सुनील गावस्कर खुद भी सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित हैं। उनका मानना है, "एक दिन वह जरूर आयेगा जब सचिन की बल्लेबाजी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तहलका मचा कर रख देगी।"

शानदार शुरुआत: ८६ के जूनियर क्रिकेट मैच में सचिन के शानदार प्रदर्शन ने नयी उम्र के चैंपियन क्रिकेट खिलाड़ियों को भी सचिन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनमें से बहुतेरे तो यह राय देने पर मजबूर हो गये कि सचिन को समय इधर-उधर लगाने के बजाय रणजी ट्राफी टीम में प्रवेश पाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं चैंपियनों में से एक खिलाड़ी दिलीप वेंगसरकर सचिन की सहायता के लिए आगे बढ़े और उसे रणजी ट्राफी टीम में शामिल कराने में सफल भी हुए। वैसे भी सचिन को प्रवेश तो मिलना ही था, क्योंकि क्रिकेट आलोचकों से लेकर दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों जैसे पाली उम्रीगार, बापु नादकर्णी तथा सुनील गावस्कर ने सचिन की प्रतिभा को काफी उछाला था और बंबई की रणजी ट्राफी टीम में उसके दाखिले के लिए अपनी संस्तुति पेश की थी। ये दिग्गज चाहते थे कि सचिन क्रिकेट के बचकाना माहौल से निकलकर उच्च श्रेणी के क्रिकेट माहौल से परिचित हो, ताकि उसके बारे में सही निर्णय लिया जा सके।

दिग्गजों की प्रशंसा रंग लायी और शिवाजी पार्क के उभरते सितारे सचिन को अपनी चमक दिखाने का मौका मिल ही गया। गाइल्स शील्ड के प्रारंभिक प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करते हुए सचिन रणजी ट्राफी टीम में प्रवेश पाने के करीब पहुंच गया। १६८८ में प्रशिक्षण की विभिन्न चरणों को पार करते हुए आखिरकार सचिन बंबई की रणजी ट्राफी टीम के लिए चुन ही लिया गया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के इस आयोजन में सचिन ने ११ दिसंबर को गुजरात के खिलाफ अपने हाथ की कला दिखाते हुए शानदार शतक पूरा किया और १५ वर्ष, ७ माह, १७ दिन की कम उम्र में शतक पूरा करने वाला भारत का पहला क्रिकेट खिलाड़ी बना। सचिन के इस शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों वैसंत अमलदी तथा राजन बाला ने सचिन की भूरि-भूरि प्रशंसा की और सचिन से भविष्य में भी इसी तरह का प्रदर्शन करते रहने की आशा जाहिर की।

खूबियां ही खूबियां: इसमें संदेह नहीं कि सचिन एक अनुभवी बल्लेबाज की सभी खूबियों का मालिक है। बल्ले की ओर बढ़ती हुई गेंद की तीव्रता तथा उतार-चढ़ाव को भांपना उसे भलीभांति आता है। यही नहीं, किस गेंद को बल्ले के किस भाग से खेला जाना है तथा गेंद की तीव्रता को मद्देनजर रखते हुए उसे किस दिशा में मोड़ना है, इस कला में सचिन पूरी तरह निपुण है। उसके खेल में खास बात यह पायी गयी कि पिच पर जिस समय सचिन खेलने की मुद्रा में मौजूद होता है उसकी प्रकृति में एक अजीब-सी खिलाड़ी गंभीरता होती है जिसे देखकर सुनील गावस्कर की याद आती है। खतरा मोल न लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना तथा हर गेंद पर रन बनाने की टोह में लगे रहना सचिन की खूबियों में शामिल है। हर ऐतबार से सचिन एक होनहार लड़का है। स्कूली शिक्षा में भी उसकी रुचि है। शारदा आश्रम मंदिर का छात्र होने के नाते कालेज के अध्यापकगण भी सचिन के मनोबल को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते हैं।

ऐसा नहीं है कि स्कूल के मैदान से निकलकर उच्च स्तर के मैचों की पिच पर शानदार प्रदर्शन करने वाला सचिन ही पहला कम उम्र खिलाड़ी है। ५० के दशक में सुधीर वियल पाटकर, ६० के दशक में रोमेश नागदेव तथा वजीर अली भी ऐसे कुछ नाम थे जिन्होंने स्कूल के मैचों में काफी शानदार प्रदर्शन किये थे, किंतु जब उन्हें उच्च स्तरीय मैचों में प्रवेश दिया गया, तो उनसे निराशा का सामना करना पड़ा। किंतु सचिन की बात उन लड़कों जैसी नहीं है। शिवाजी पार्क के खेलों से लेकर रणजी ट्राफी टीम के मुकाबलों तक उसने अपनी निरंतरता को कायम रखा और भारतीय क्रिकेट जगत को अपने खेल का विश्वास दिला दिया। १४ वर्ष की कम उम्र में ही विभिन्न मैचों में सचिन ने २७६, १५६, १५६, १२३, १२३, १६७, १५० तथा ३२६ रनों का शानदार स्कोर अर्जित करके अपने बल्ले की कला का परिचय देना शुरू कर दिया था। रणजी ट्राफी टीम के लिए शानदार खेल खेलकर उसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सचिन भी एक दिन सुनील गावस्कर की तरह क्रिकेट की दुनिया में चमकने की ठान बैठा है?

कम उम्र के इस नौजवान खिलाड़ी से क्रिकेट जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। अब लोग उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शृंखलाओं में भारतीय टीम के उभरते गावस्कर के रूप में देखा जायेगा।

—सुरेश सरैया

छाया: बिमोर

देश

१ जनवरी : साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक पर झगड़ा, एक मजदूर मृत, रंगकर्मी सफदर हाशमी घायल। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका से शांति सेना की क्रमिक वापसी का निर्णय।

२ जनवरी : राष्ट्रपति आर वेंकटरमण द्वारा केहर की दया याचिका रद्द, सतवंत और केहर के खिलाफ काला वारंट जारी। देवीलाल द्वारा जनता दल और भाजपा में चुनावी तालमेल होने की घोषणा। क्रिकेट खिलाड़ी नवजोत सिद्धू और उनके मित्र की अंतरिम जमानत मंजूर। रंगकर्मी सफदर हाशमी का निधन।

३ जनवरी : भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन समझौते की अवधि न बढ़ने के संकेत। जत्थेदारों द्वारा दल के अध्यक्ष सुरजीत सिंह बरनाला का इस्तीफा नामंजूर। कर्नाटक जनता पार्टी का जनता दल में विलय।

४ जनवरी : सतवंत और केहर को ६ जनवरी को फांसी देने का निर्णय। जनता दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाने की मांग। आंध्र प्रदेश के गृहमंत्री कोदेला शिव प्रसाद राव द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा।

५ जनवरी : त्रिपुरा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर। भाजपा नेता तरसेम सिंह बहार की आतंकवादियों द्वारा हत्या।

६ जनवरी : सतवंत और केहर को तिहाड़ जेल में फांसी, अंतिम संस्कार भी जेल में ही संपन्न,

७ जनवरी : विज्ञान का अत्यधिक सैनिक उपयोग बंद करने का राजीव गांधी द्वारा आह्वान। सीबीआई द्वारा पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल पुरी सुरक्षा संबंधी जानकारियां इधर-उधर करने के आरोप में गिरफ्तार।

८ जनवरी : भारत का पहला लंबी दूरी का प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' परीक्षण उड़ान के लिए तैयार।

९ जनवरी : कर्नाटक जनता पार्टी के जनता दल में विलय पर हंगामा, विभाजन के आसार। आंध्र प्रदेश में कांग्रेसियों द्वारा १२ घंटे का अनशन।

१० जनवरी : विपक्षी सांसद डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा हेगड़े पर नाजायज ढंग से ३५० करोड़ रुपए कमाने का आरोप। राष्ट्रपति द्वारा २५ प्रसिद्ध कलाकार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित।

११ जनवरी : सात विपक्षी दलों द्वारा वामपंथी और लोकतांत्रिक कार्यक्रमों के लिए जनमत जगाने के फैसले पर अभियान समिति का गठन, लोकदल (ब), कांग्रेस (स) और जनमोर्चा शामिल।

१२ जनवरी : लोकसभा सदस्य तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजमंगल पांडे जनता दल में शामिल।

१३ जनवरी : जम्मू में हिंसा और आगजनी, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। माकपा सांसद टीएस गुरूंग की हत्या। भाजपा नेता राजेंद्र जैन की बेड़ौत (मेरठ) में हत्या।

१४ जनवरी : राजस्थान राज्य कर्मचारियों द्वारा 'जेल भरो' अभियान शुरू करने की धमकी। जम्मू में तनाव बढ़ा, सेना तैनात, नागाओं के प्रथम स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत।

१५ जनवरी : २१ वर्षीय चिकित्सा छात्रा कल्पना पंडित ८९ की मिस इंडिया बनीं। प्रसिद्ध मराठी लेखक एसजे जोशी का निधन।

सफदर हाशमी

सुब्रह्मण्यम स्वामी

सम्राट हिरोहितो

बेनजीर भुट्टो

विदेश

१ जनवरी : रियो डी जिनेरो के कोपाबाना तट से दूर समुद्र में यात्री नौका डूबी, सौ मृत। कराची (पाकिस्तान) के दक्षिणी भाग में पुनः जातीय हिंसा भड़की।

२ जनवरी : क्यूबा ने समाजवादी क्रांति की तीसरी वर्षगांठ मनायी। बीस हजार अमरीकियों द्वारा सोवियत नेता को हस्ताक्षरयुक्त नववर्ष बधाई प्रेषित। बेनजीर भुट्टो द्वारा पाक परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण होने का ऐलान।

३ जनवरी : पाकिस्तानी परमाणु बम के कथित निर्माता प्रोफेसर अब्दुल कादिर खां को अवांछित घोषित कर हालैंड सरकार द्वारा देश-निकाला। ईरान द्वारा अफगानिस्तान से सोवियत सेना शीघ्र हटाने का आग्रह। चेकोस्लोवाकिया के लापता राजनयिक ब्लास्तिमिर लुडविक द्वारा ब्रिटेन में शरण।

४ जनवरी : भूमध्य सागर पर अमरीका ने लीबिया के दो विमान गिराये, लीबियाई नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी द्वारा बदला लेने की घोषणा। श्रीलंका के नये राष्ट्रपति राणासिंघे प्रेमदास द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन।

५ जनवरी : अमरीका द्वारा लीबिया के रासायनिक हथियार बनाने वाले संयंत्र पर हमला न करने की घोषणा। बर्मा के छात्रों द्वारा जार्ज बुश से सहायता की मांग।

६ जनवरी : नामीबिया में राष्ट्र संघ की सेना घटाने का दक्षिण अफ्रीकी सीमावर्ती देशों द्वारा विरोध। सोवियत-मुजाहिद वार्ता विफल। श्रीलंका संसदीय चुनाव के लिए १२०० नामांकन।

७ जनवरी : जापान के ८७ वर्षीय सम्राट हिरोहितो का निधन। गद्दाफी द्वारा अमरीका से बातचीत के लिए तैयार होने का आग्रह।

८ जनवरी : चीन के विदेश मंत्री छेन छी छन द्वारा भारत से अच्छे संबंध की जरूरत पर जोर। रूस और अमरीका द्वारा रासायनिक हथियार नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ।

९ जनवरी : बेरूत में शियागुटों के बीच संघर्ष, ७० मृत। अंगोला से क्यूबा की सैन्य वापसी शुरू। अमरीकी रक्षा बजट में दो प्रतिशत वृद्धि।

१० जनवरी : जापान सरकार द्वारा हिरोहितो की अंत्येष्टि पर आठ करोड़ डालर खर्च करने का निर्णय। बेनजीर भुट्टो मक्का, मदीना की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना।

११ जनवरी : रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में १५० से ज्यादा देशों द्वारा पूर्ण प्रतिबंध के लिए सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी।

१२ जनवरी : सुरक्षा परिषद में निर्गुट देशों के लीबिया संबंधित प्रस्ताव पर वीटो। अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी पुनः शुरू। ब्रिटेन ट्यूनीशिया स्थित राजदूत यासिर अराफात से मिले।

१३ जनवरी : फिलिस्तीन के लिए इस्रायल के प्रधानमंत्री इसहाक शमीर द्वारा शांति योजना की घोषणा। अमरीका के भावी राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा मंत्रिमंडल का चयन।

१४ जनवरी : इंग्लैंड ने फिलिस्तीन के मसले पर नर्म रवैया अपनाया। विवादास्पद रूसी क्षेत्र नागार्नो-काराबख को मास्को के अधीन करने का फैसला।

१५ जनवरी : बांग्लादेश के औद्योगिक नगर टोंगी के निकट भीषण रेल दुर्घटना, २०० मृत, हजारों घायल। वियतनाम के विदेश उपमंत्री दिन नो लियम चीन पहुंचे, चीन-वियतनाम संबंधों में सुधार के संकेत।

कुतिया खोजो अभियान

यह बात दूसरी है कि हमारी पुलिस आम इंसान के साथ इंसानी सलूक नहीं कर पाती, लेकिन उस पर यह कोई तोहमत नहीं लगा सकता कि वह खास लोगों और उनके कुत्तों के साथ बदसलूकी करती है या उनकी सहायता नहीं करती है। अब देखिए न कानपुर की पुलिस ने पिछले दिनों एक नन्ही झबरी कुतिया को खोजने के लिए 'कुतिया खोजो अभियान' छेड़ कर कैसा ऐतिहासिक काम कर दिखाया है!

दरअसल, हुआ यह कि पिछले दिनों कानपुर के मोतीझील पार्क में कुत्तों की एक अखिल भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से ९८ सजी-संवरी कुतियों और एक-से-एक बांके कुत्तों ने भाग लिया। सारे लोग तो

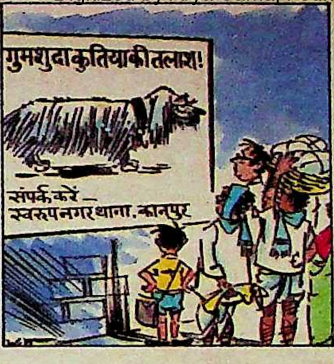
गुमशुदा कुतिया की तलाश!
संपर्क करें —
स्वरूपनगर थाना, कानपुर

प्रदर्शनी का आनंद ले रहे थे, लेकिन एक लोभी श्वान प्रेमी की नजर नन्ही-मुन्नी पामेरियन झबरी कुतिया पर थी। नतीजतन प्रदर्शनी के बीच से ही वह पुलिस-पीएसी के बीच से न जानें कब उसे लेकर चंपत हो गया। आठ हजार रुपए कीमतवाली इस मोहक कुतिया के गायब होते ही तहलका मच गया। कुतिया मालिक के कानपुर के स्वरूपनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते ही पुलिस ने युद्धस्तर पर कुतिया को खोजने का काम शुरू कर दिया और चप्पा-चप्पा छान मारा।

११२ वर्षीय छात्रा

यों तो पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई किसी भी उम्र में पढ़-लिख सकता है। लेकिन दोनों पैर कब्र में होते हुए भी कोई पढ़ने का शौक पाले, तो गालिब की लाइन 'आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमां होंगे' याद आना स्वाभाविक है। पर साहब शौक-तो-शौक है। जापान की सबसे वयोवृद्ध ११२ वर्षीय महिला मित्सु फ्यूजीसावा को यही शौक चर्राया है। अगले वर्ष अप्रैल से वे एक खुले विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की सोच रही हैं। फ्यूजीसावा चूंकि अपने को दीर्घायु और चुस्त-दुरुस्त रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने शारीरिक विज्ञान पढ़ने पर काफी जोर दिया है। दरअसल, उन्हें पढ़ने की प्रेरणा शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर से मिली, तभी से उन्होंने पढ़ने का मन बना लिया। इस उम्र में भी वे स्वस्थ हैं और बिना किसी के सहारे के चल-फिर सकती हैं। उल्लेखनीय है कि १९८५ में स्थापित इस विश्वविद्यालय में ९५ वर्ष की एक दूसरी महिला सबसे बूढ़ी छात्रा रही है।

केक हो तो ऐसा

बड़े दिन के अवसर पर प्रायः हर साल ही तरह-तरह के केक बनाये जाते हैं—एक-से-एक लज्जतदार और जायकेदार। लेकिन हर तरह के केक खाने के लिए ही तैयार किये जाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 'ग्लोब केक' नाम का एक ऐसा केक बनाया गया, जिसको प्रदर्शनी में रखा गया। सबसे मजेदार बात यह है कि यह खाने के लिए नहीं, वरन शांति का संदेश देने के लिए इसे तैयार किया गया था।

२४९६० अंडों, ७८० किग्रा चीनी, ५८५ किग्रा मक्खन, १३० किग्रा फ्रूट पावडर और १९४ किग्रा कोकोआ से बना संसार का यह विशालतम केक ८.५ मीटर ऊंचा और ३.५ मीटर चौड़ा था। इस केक की सबसे आकर्षक चीज थी, इस पर बने संसार के १६ महापुरुषों के चित्र—जिनमें महात्मा गांधी, पोप जान पाल द्वितीय, रोनाल्ड रीगन, मिखाइल गोर्बाचेव, डेसमंड टूटू, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला,

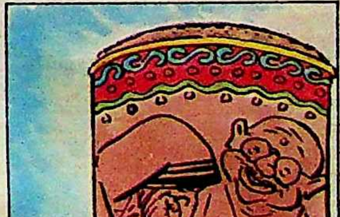

बाब गेल्डोफ, राष्ट्रपति सुहार्तो और मदर टेरेसा प्रमुख थे।

इस केक को बनानेवाली इंडोनेशिया की मशहूर बावर्ची नीला चंद्रा ने कहा है कि इसके निर्माण के पीछे विश्वशांति और भाईचारा की भावना जगाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है।

गुरु नहीं गुरुघंटाल

गुरु-शिष्य परंपरा पर हमारे यहां पोथियां रंगी पड़ी हैं और भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन पर रस्मी 'अध्यापक दिवस' के मौके पर इस परंपरा पर लजीज भाषण भी दिये जाते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य आज किस मकाम पर पहुंच गये हैं, इसके किस्से आये दिन सुने जाते हैं। यहां भी एक ऐसे ही गुरु का किस्सा है, जो गुरु कम गुरुघंटाल ज्यादा हैं। केरल के एनएसएस कालेज के अंग्रेजी प्रोफेसर वीएन गंगाधरन नायर को ऐसे ही रूप में देखा जा रहा है।

हुआ यों कि केरल विश्वविद्यालय की बीए की परीक्षा में 'अंग्रेजी साहित्य के इतिहास' के परचे में एक परीक्षार्थी शेक्सपीयर और एलियट को तो भूल गया और उसके बदले प्रश्नों के उत्तर के रूप में मलयाली फिल्मों के सुंदर-सुंदर-गीत लिख दिये। इस पर प्रो० नायर इतने रीझे कि परीक्षार्थी को नंबर भी दे दिये। लेकिन प्रो० नायर की यह 'उदारता' उन्हें काफी महंगी पड़ी है। विश्वविद्यालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दी है कि सिंडीकेट के सख्त निर्देश पर भी उन्होंने अपनी लापरवाही का उचित उत्तर अब तक क्यों नहीं दिया?

—संयोजन: डा० मुश्ताक अली

नाम का जादू

कोमल महुआकर छाया: एन प्रसाद

'मिली', 'देस-परदेस', 'घुंघरू' आदि फिल्मों की बाल अभिनेत्री कोमल महुआकर के किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उसे साड़ी-ब्लाउज पहना कर राजश्री फिल्म्स ने हीरोइन तो बना दिया, लेकिन दूसरे फिल्म निर्माताओं ने छोटी-मोटी भूमिकाओं के काबिल भी उसे नहीं समझा। 'नगीना' और 'मेरी अदालत' जैसी फिल्मों में मामूली भूमिकाएं निभाने के बाद अपने कैरियर के बारे में वह गंभीरता से कोई निर्णय लेती कि मद्रास की भाग्यराज फिल्म्स ने उसे 'सर, आई लव यू' में काम करने का आफर दिया। वह फिल्म तो झगड़े में फंसी रह गयी, लेकिन भाग्यराज के संपर्क में आते ही कोमल का भाग्य बदल गया। वह कोमल महुआकर की जगह रूपिणी के नाम से सुपरस्टार बन गयी। देर से सोकर जगने के आदी बंबइया फिल्म निर्माताओं ने अब रूपिणी को हिंदी फिल्मों में लाने की मुहिम शुरू कर दी है। अब अपने घर पर पहरा देने वाले इन फिल्म निर्माताओं के सामने रूपिणी अपनी मनचाही शर्तें रखनी शुरू कर दे, तो उसका क्या दोष, आखिर उसे नकारनेवाले भी तो ये ही लोग थे।

'जन्नत' ही सही!

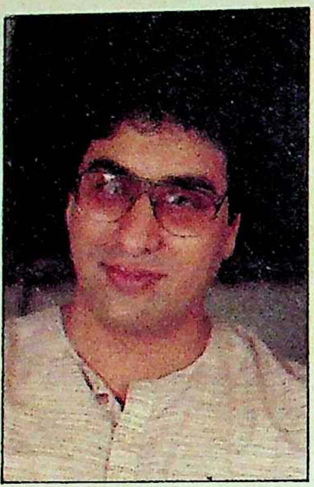

तलत अजीज छाया: रयिजीत घटक

अपनी गजलों से लाखों-करोड़ों दर्शकों की वाहवाही लूटनेवाले तलत अजीज की हीरो बनने की दिली ख्वाहिश अंततः 'अंधा-युद्ध' के निर्माताओं ने पूरी कर ही दी—'जन्नत' का नायक बनाकर। १९८७ में एक निर्माता ने उन्हें डिंपल के साथ बतौर नायक साइन किया और शूटिंग की तैयारी कर ही रहे थे कि 'इंसाफ' की सफलता ने डिंपल को सुपरस्टार बना दिया। अमिताभ के साथ फिल्में साइन करने के बाद डिंपल उस फिल्म को भी भूल गयी और उसके साथ नायक तलत अजीज को भी।

अब निर्माताओं का कहना है कि अगर तलत भी एक हाथ में स्टेनगन थाम कर दूसरे हाथ से दर्जनों खलनायकों को चित कर देने, मिथुन चक्रवर्ती और जीतेंद्र की तरह 'कमर-मटकाऊ डांस' तथा गोविंदा की तरह हीरोइनों का बेमतलब चुंबन लेने में महारत हासिल कर लें, तो १९८९ के सुपर स्टार बन सकते हैं। 'किस-डांस-रोमांस' से तो तलत को परहेज नहीं, लेकिन हारमोनियम-तानपूरा संभालने वाले नाजुक हाथों में वे स्टेनगन थाम पायेंगे, यह तो आनेवाला समय ही बतायेगा!

शबाना की उलझन

शबाना आजमी छाया: एनएन प्रताब

बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की जितनी खुशी शबाना आजमी को हुई, उतनी ही उलझन भी। उलझन इसलिए कि वे तारिक अली की फिल्म 'बेनजीर भुट्टो' में बेनजीर की भूमिका निभाकर महात्मा गांधी की भूमिका निभानेवाले बेन किंग्सले के समकक्ष पहुंच जातीं। तारिक अली ने शबाना की बेनजीर से कई (संक्षिप्त) मुलाकातें भी करा दी थीं, ताकि वे उन्हें अच्छी तरह आब्जर्व कर सकें। एक लंबा मुलाकात-सेशन अभी बाकी ही था कि बेनजीर पहले विवाह, फिर मातृत्व और उसके बाद आम चुनाव में फंस गयीं। अब क्योंकि वे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं, इसलिए निर्माता-निर्देशक तारिक अली को नये सिरे से उनसे (राजनयिक) अनुमति लेनी पड़ेगी और बदले हुए हालात में पटकथा को नये सिरे से लिखना पड़ेगा।

तारिक अली तो मुसीबत में पड़े ही हैं, असली उलझन में तो शबाना आजमी हैं। शबाना को डर है कि कहीं सिमी ग्रेवाल भी बेनजीर पर फिल्म बनाने की हामी न भर लें, क्योंकि शबाना को तो वे अपनी फिल्म में लेने से रहीं!

संजय खान का मोह-भंग

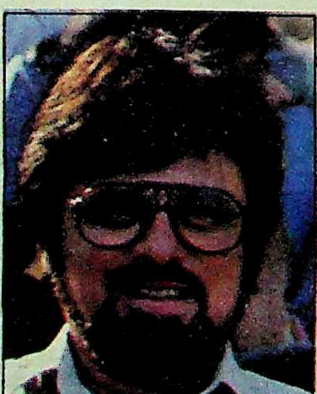

संजय खान छाया: प्रदीप चंद्र

पुणे, बंबई तथा बंगलौर के घुड़दौड़ों में अपने घोड़ों व जाकी का कमाल दिखलानेवाले अभिनेता-निर्देशक-निर्माता संजय खान फिल्म इंडस्ट्री की अनिश्चितता से कुछ इस कदर निराश हुए कि उन्होंने अपनी बहुसितारीय फिल्म 'सरजमीं' का निर्माण फिलहाल ठप कर दिया है। अपने भाई फीरोज खान की 'दयावान' के बाक्स आफिस पर बुरी तरह से पिट जाने के कारण 'सरजमीं' के नायक विनोद खन्ना की बाक्स आफिस गारंटी से उनका विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया, उधर रेसकोर्स के उनके घोड़े भी मानो जैकपाट जीतने का फार्मूला भूल गये हैं। अब यह उनका दुर्भाग्य ही है कि जहां फीरोज़ खान निर्देशित फिल्में, सतही होने के बावजूद, बाक्स आफिस पर चमत्कार दिखलाया करती थीं, वहीं संजय खान निर्मित-निर्देशित 'चांदी-सोना', 'अब्दुल्ला द ग्रेट', 'काले धंधे गोरे लोग' बहुउद्देशीय फिल्म (बकौल संजय खान) होने के बावजूद पिटती रहीं।

संभवतः उन्हें अब तो 'टीपू सुल्तान' (टीवी सीरियल) ही मोह-भंग की सुरंग से निकाल सकता है।

—अखबारी लाल

श्री [illegible] द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस, ३-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

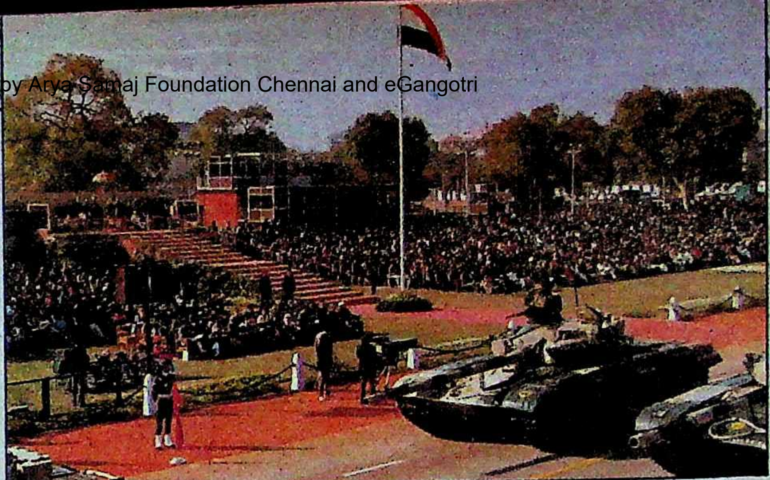

४०वां गणतंत्र दिवस देश की सैन्य शक्ति और संस्कृति के गरिमामय प्रदर्शन के साथ उल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने राजपथ पर विशेष रूप से बनाये गये मंच से परेड की सलामी ली (दायें)। इस अवसर पर वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव गुयेन वान लिन्ह मुख्य अतिथि थे। नौ बजकर ५८ मिनट पर राष्ट्रपति के सलामी मंच पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा की अगवानी की।

सेना के ध्वज फहराते चार हेलीकाप्टरों ने दर्शकों पर पुष्पवर्षा की। परेड का नेतृत्व मेजर जनरल विनोद बघवार ने किया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों व सरकारी प्रतिष्ठानों की विकास की झांकियां भी दिखायी गयीं, जिनमें उत्तर प्रदेश (दायें बीच में), गोवा (सबसे नीचे) और हिमाचल प्रदेश (नीचे) की झांकियां विशेष आकर्षक थीं।

छाया : सुनील सक्सेना, गिरीश श्रीवास्तव

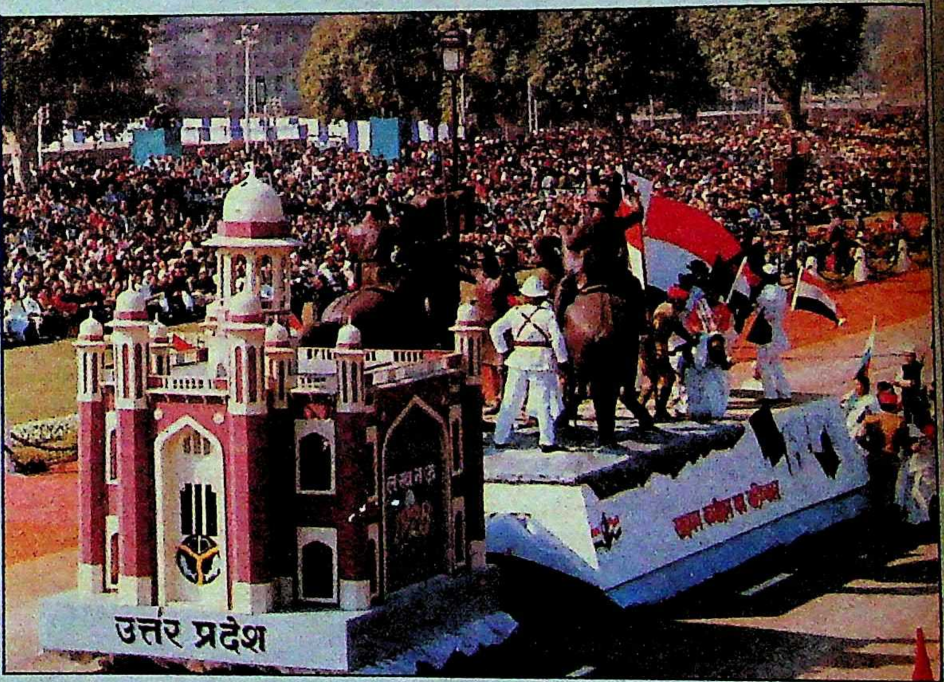

संगम क्षेत्र में स्नान करते श्रद्धालु

छाया : राजेंद्र कुमार

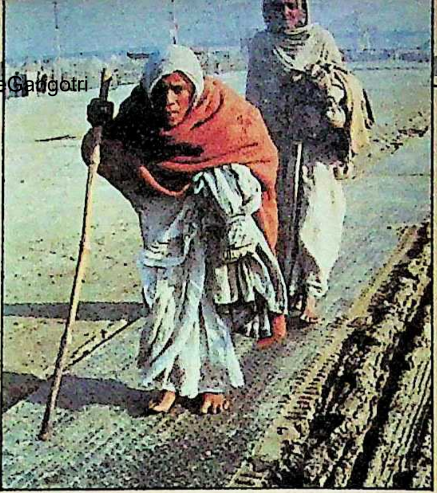

आस्था का बल :
स्नान के लिए अग्रसर वृद्ध महिलाएं

छाया : विनोद कुमार

कर्म की प्रतीक गंगा, उत्साह की प्रतीक जमुना और विवेक की प्रतीक सरस्वती (लुप्त) के संगम क्षेत्र प्रयाग में १४ जनवरी मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ दुनिया का विशालतम कुंभ मेला विविधताओं से परिपूर्ण है। जहां एक ओर नंग धड़ंग वीतरागी नागा संन्यासी हैं, तो दूसरी ओर हीरे मोती स्वर्णजड़ित आभूषणों से सज्जित तांत्रिक व धर्मगुरु भी इस मेले में अपना आसन जमाये बैठे हैं। एक ओर भारत के कोने-कोने से आये करीब एक लाख कल्पवासी तमाम असुविधाओं के बावजूद माघ मास की इस कड़कड़ाती ठंड में भी दो बार गंगा स्नान कर साधु-संतों का दर्शन करते व प्रवचन सुनते हुए कल्पवास का धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं, तो कुछ अतिविशिष्ट कल्पवासी तमाम ऐशो-आराम के साथ इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। बौने, अष्टावक्र जैसे विचित्र आकार और नाकनक्श के संन्यासी ही मेले में आकर्षण का केंद्र नहीं हैं, बल्कि कांटों पर लेटे, एक पैर पर खड़े या एक हाथ उठाये अथवा रेत में मुंह गड़ाये हठयोगी संन्यासी भी कौतूहल का विषय बने हुए हैं। एक ओर दुकानों की तरह सजी धार्मिक संस्थाओं और अनेक शंकराचार्यों, मंडलेश्वरों, तांत्रिकों और अखाड़ों के पण्डाल हैं, तो दूसरी ओर झूंसी के पूर्वी क्षेत्र में इस सारी गहमागहमी से दूर विरक्त साधुओं की कुटियाएं हैं। गंगा पार मेला क्षेत्र से दो किलोमीटर आगे उत्तर में देवरहा बाबा अपने मचान पर एकाकी विराजमान हैं, लेकिन उनके प्रति लोगों की इतनी आस्था है कि दर्शन करने और सिर पर पांव टिकवा कर आशीर्वाद लेनेवालों का तांता वहां लगा रहता है। मेला क्षेत्र के अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन अक्षय भंडारा चला करता है, तो श्रद्धालुओं के कारण मेले की चमक-दमक से दूर रहनेवाले गुफा-निवासी एकांतवासी विरक्त साधुओं को भी भोजन की कमी नहीं रहती। इन सबके बावजूद विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव का रंग फीका माना जा रहा है, क्योंकि जितने कल्पवासियों और स्नानार्थियों के आने की उम्मीद की गयी थी, उतने श्रद्धालु नहीं आये।

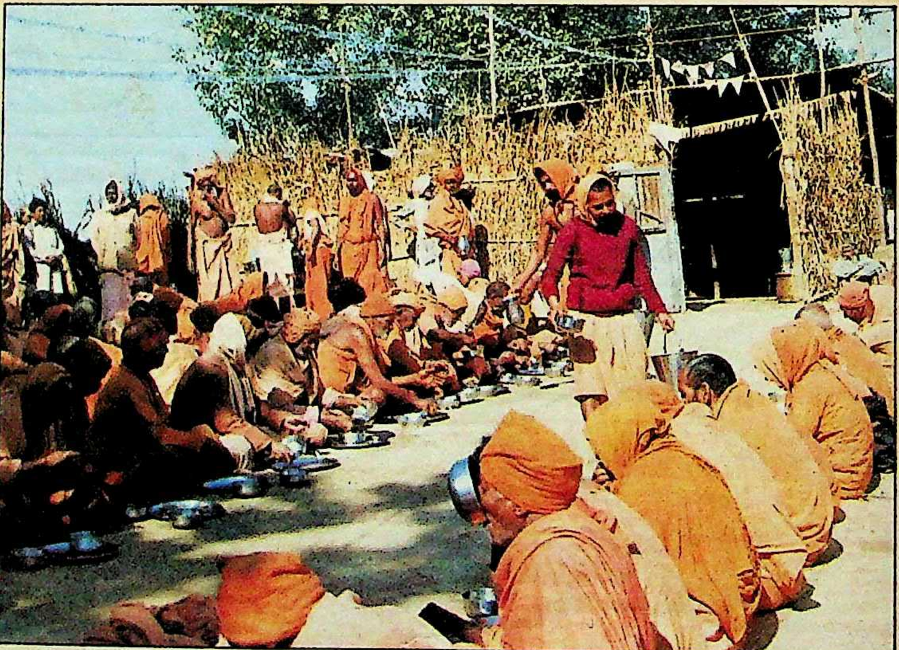

विरक्त साधुओं का समवेत भोजन

छाया : वसीमुल हक

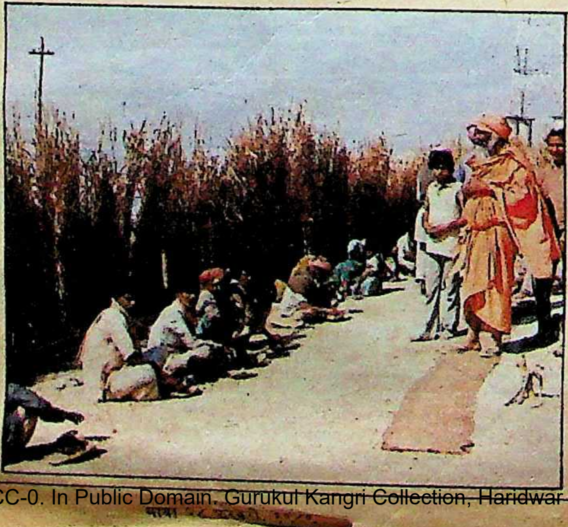

अन्नक्षेत्र में श्रद्धालुओं
का भंडार साथ में अमरजीत

छाया : विनोद कुमार

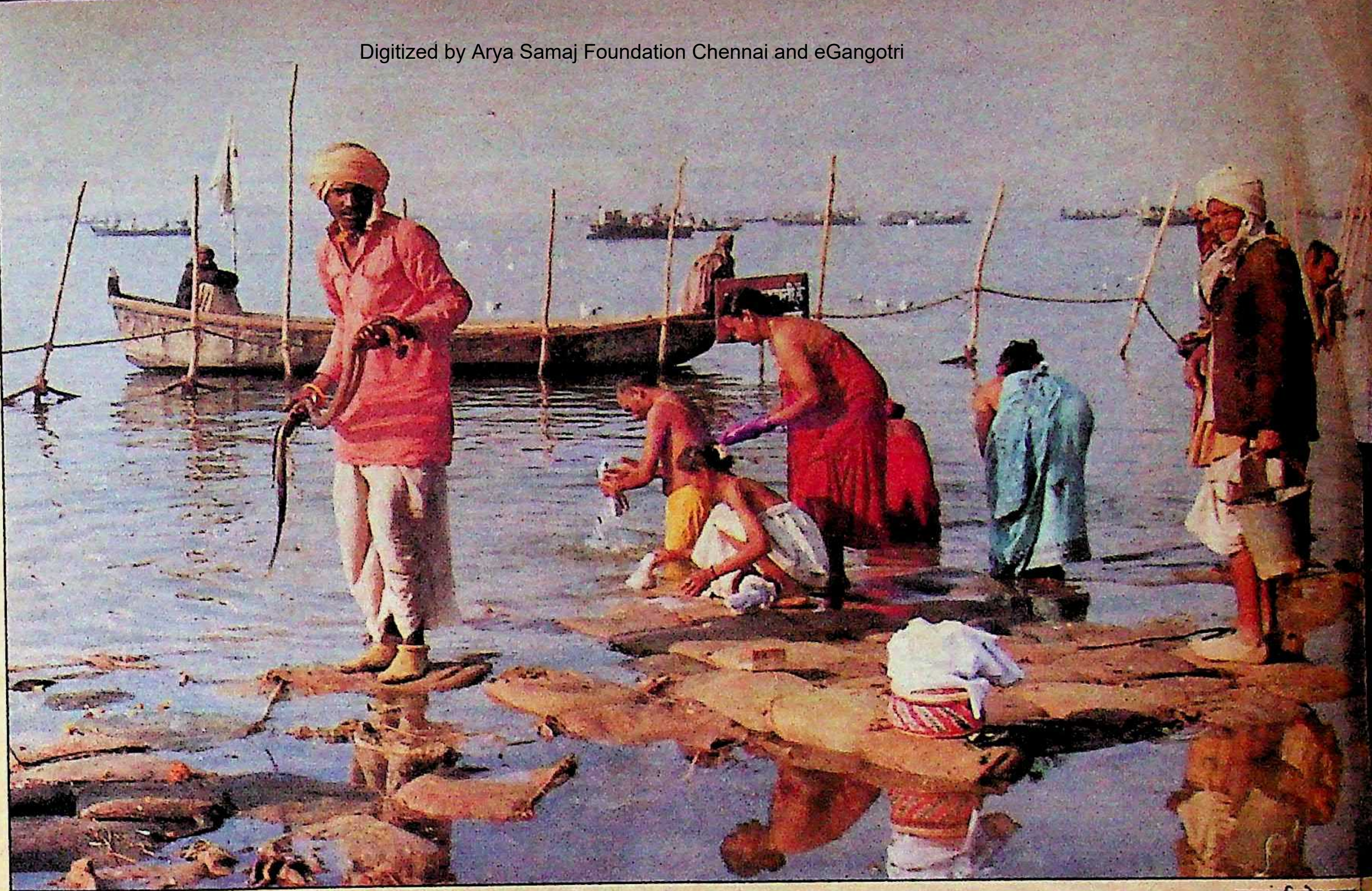

सर्प स्नान

छाया : विनोद कुमार

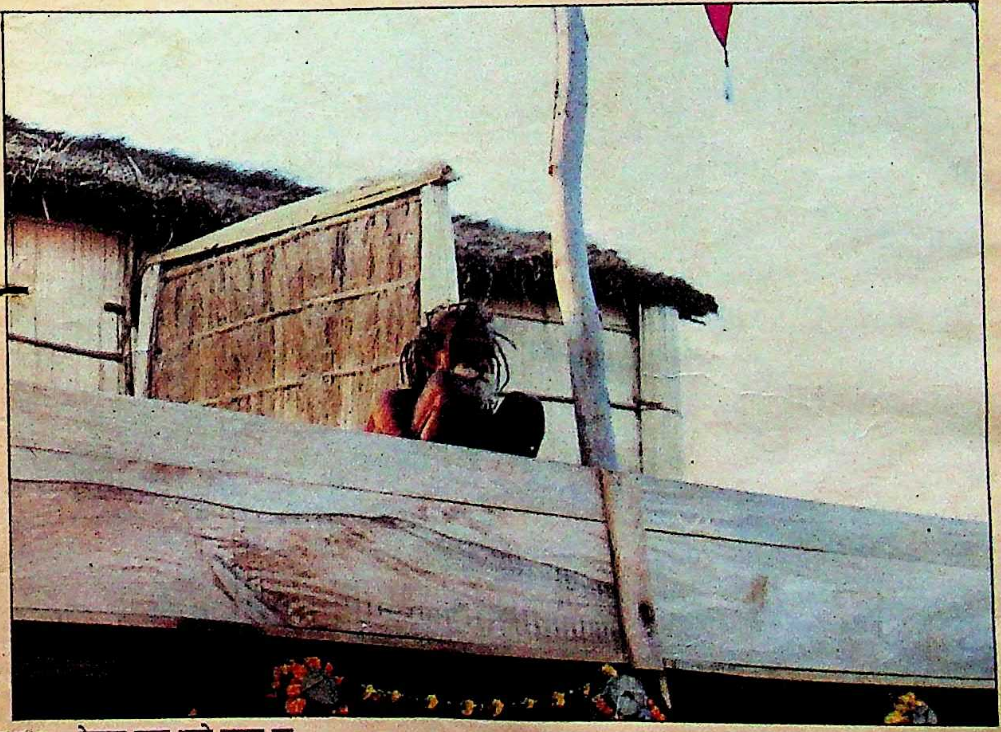

देवरहा बाबा अपने मचान पर

छाया : विनोद कुमार

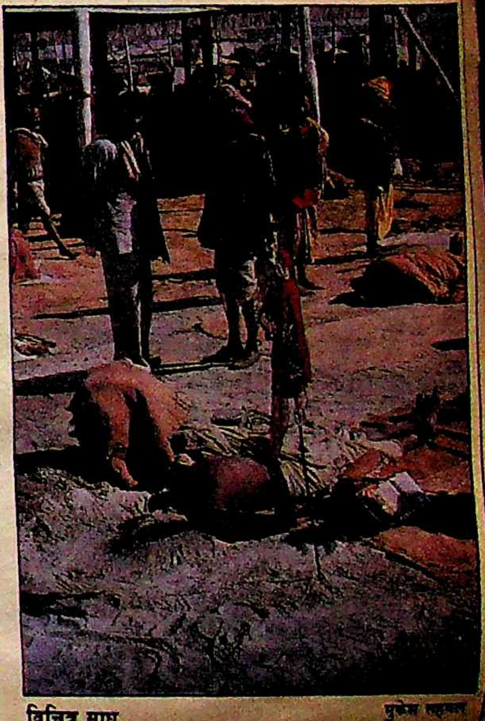

विचित्र साधु

मुकेश [illegible]

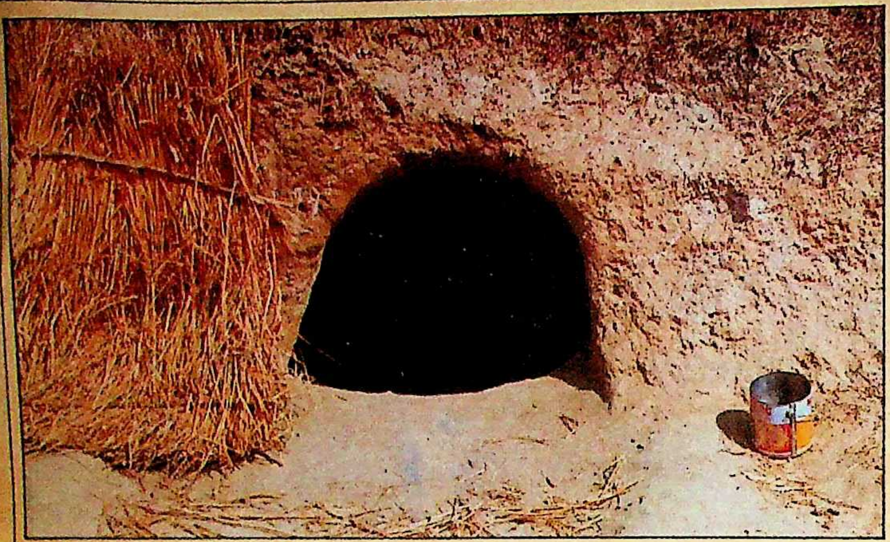

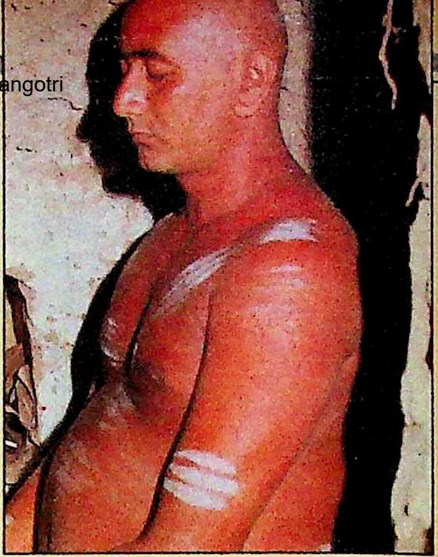

एकाकी गुफा निवासी साधु (ऊपर दायें)

छाया : वसीमुल हक़

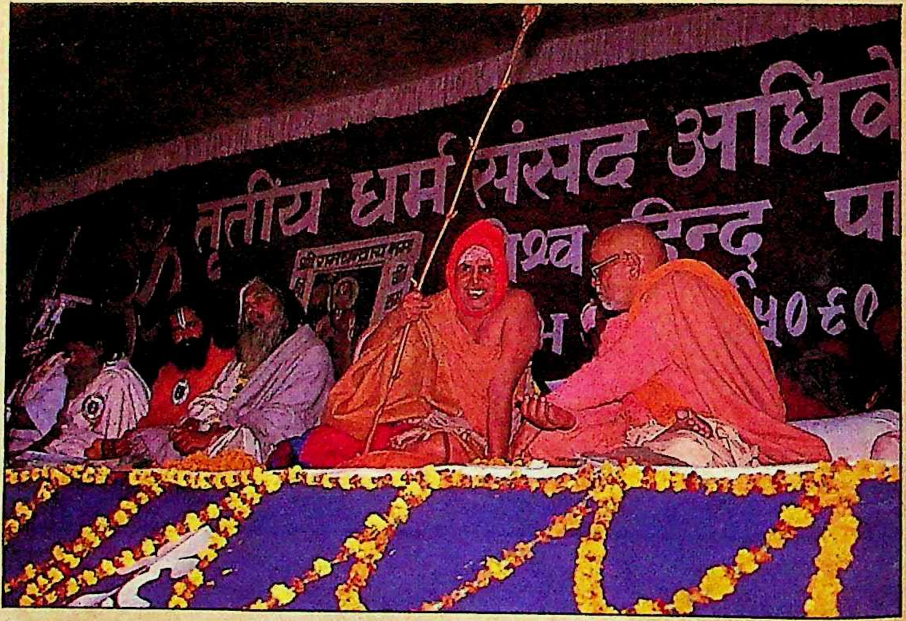
तृतीय धर्म संसद अधिवे

विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित तृतीय धर्म संसद में कांची के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती

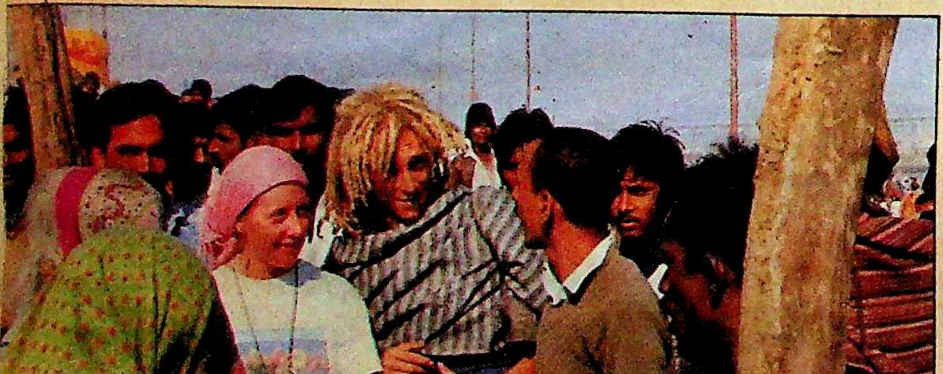

कुंभ मेले में विदेशी

छाया : मनमोहन शर्मा

महाकुंभ

शताब्दी का सबसे बड़ा धर्म महोत्सव

जाति, धर्म, नर-नारी, छोटे-बड़े के सभी विभेद खतम : श्रद्धालु संगम में

छाया : राजेंद्र कुमार

छह फरवरी सही सलामत गुजर गयी, जबकि सोमवती अमावस्या के महास्नान पर्व पर एक-डेढ़ करोड़ स्नानार्थियों का ऐसा जनसमुद्र उमड़ा था कि सबके अनुमान ध्वस्त हो गये । ४ फरवरी तक विश्व के विशालतम मेले के रूप में विख्यात इस महाकुंभ में तो सामान्य माघ मेलों जितनी भी रौनक व भीड़भाड़ नहीं थी, लेकिन ४ फरवरी की सुबह से जिस कल्पनातीत जन सैलाब का हर दिशा से संगम क्षेत्र में आना शुरू हुआ, उसका अटूट तांता ७२ घंटों तक बराबर बना रहा। मेले की व्यवस्था में मुस्तैद पुलिस, सरकारी अफसर व स्वयंसेवी संस्थाएं ही नहीं, बल्कि हादसे की आशंका से भयभीत आम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि इतने विशाल जनसमुद्र का गंगा व संगम मिलन इतनी सुव्यवस्था और शांति से कैसे संपन्न हो गया ? बेजान पड़े महाकुंभ में अब नयी जान आ गयी है, लेकिन कुंभ नगर में हो क्या रहा है ? क्या विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव कुछ अपवादों को छोड़कर आर्थिक तमाशा बनकर रह गया है ? कुंभ परंपरा के आइने में महाकुंभ-१९८९ का जायजा :

सिर पर गठरी, हाथ में लोटा, जीर्णशीर्ण वस्त्र, मीलों चलने के बावजूद अनथके आगे बढ़ते अधनंगे और नंगे पांवों का अटूट सिलसिला ! उम्र की भारी देह और अभावों से टूटे मन में आस्था, विश्वास और परंपरा कितना उत्साह उंडेल देती है, इसका सजीव अहसास उसे ही हो सकता है, जिसने कुंभ के दौरान इलाहाबाद की हर सड़क के जनप्रवाह को संगम की ओर जाते देखा है। ऐसा नहीं है कि इस जनप्रवाह में मात्र दरिद्रनारायण और साधु-संन्यासी ही बह रहे हैं, साधनसंपन्न और विदेशियों की भी कमी नहीं है। यह बात दूसरी है कि किसी में आस्था का वेग है, तो किसी में इस अद्भुत नजारे को भर आंख देख लेने की उत्सुकता का ज्वार। लेकिन महाकुंभ और अर्धकुंभ से संबंधित अमृत-कलश, समुद्र-मंथन, प्रयाग, गंगा, यमुना, संगम, स्नान-दान, मोक्ष व साधु-संतों के माहात्म्य के संबंध में ऋग्वेद से लेकर मत्स्य पुराण आदि तक के उद्धरण देकर पत्र-पत्रिकाओं और कुंभ नगर स्थित धार्मिक मंचों से आज जो कुछ कहा जा रहा है, वह सामान्य समझ के बाहर की बातें हो चुकी हैं, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदल गयी हैं। अब संगम क्षेत्र में या किला स्थित तथाकथित अक्षयवट के

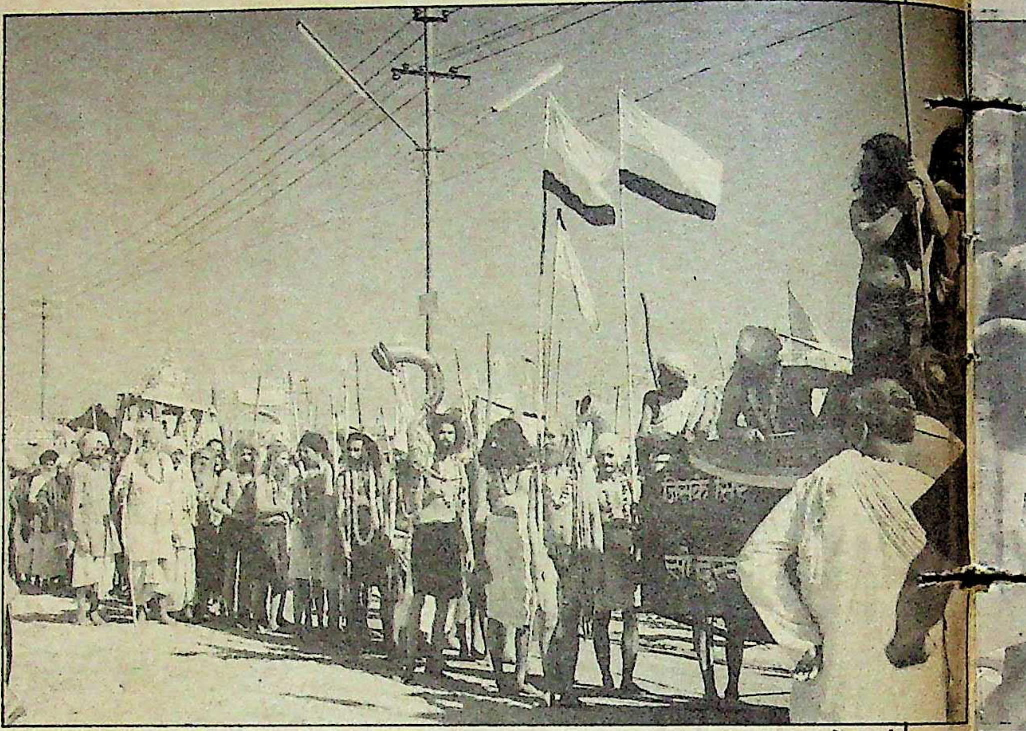

नागा संन्यासियों का शाही जुलूस

छाया : मनमोहन शर्मा

आसपास आपको नरकंकालों के ढेर दिखायी नहीं देंगे। १३ सौ साल पहले राजा हर्षवर्धन के समय भारत आये चीन यात्री ह्वेनसांग ने यह नजारा देखा था, लेकिन इधर कई पीढ़ियों से लोगों ने लोगों को 'मोक्ष' प्राप्त करने के लिए सूली पर चढ़कर या सात दिनों तक प्रतिदिन चावल का एक दाना खाकर संगम में कूदकर प्राण त्यागते नहीं देखा है। आज तो करोड़ों रुपए खर्च करके १५ हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैन्य बल तथा डाक्टरों और सफाई कर्मचारियों की लंबी फौज सिर्फ यह देखने के लिए तैनात की गयी है कि कहीं कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की गलती से ही यहां न मर जाये। इसलिए आज यह समझाना मुश्किल है कि संगम तीर्थ में प्राण त्यागने से किसी को कोई लाभ भी हो सकता है। गंगाजल की महिमा का कितना ही बखान क्यों न किया जाये, लेकिन कुंभ मेले के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डा० एके मिश्र की हिम्मत नही है कि वे यह कह दें कि यहां गंगाजल पीने से स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। जिन साधु-महात्माओं और धर्मगुरुओं की त्याग-तपस्या का बखान कुंभ मेले में हो रहा है, दरअसल कुछ अपवादों को छोड़कर आज उनके बीच पहुंचकर ही समझ में आता है कि वैभव और विलासितापूर्ण जीवन क्या होता है। आवागमन के तीव्र साधनों के बावजूद ६५ करोड़ हिंदुओं में से सिर्फ एकाध लाख के करीब कल्पवासियों की इस महाकुंभ में उपस्थिति ही यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि महाकुंभ से लोक-आस्थाएं डिग रही हैं और यह तथ्य सामान्य समझ के बाहर का विषय हो चुका है कि इस कड़कड़ाती ठंड में संगम या गंगास्नान करने से किसी को पुण्य-लाभ या मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार कुंभ-महिमा का बखान करते हुए जो शब्द कहे जा रहे हैं, वे अपने अर्थ खो चुके हैं—ऐसी बातें बोली जा रही हैं, जिन्हें सुननेवाला समझ नहीं पा रहा है और उन मान्यताओं की चर्चा की जा रही है, जिन पर आचरण करता हुआ कोई दिखायी नहीं देता।

अतः आज के जमाने में 'कुंभ' का औचित्य समझना-समझाना सरल नहीं है। लेकिन कुंभ परंपरा के माध्यम से भारतीयों की उस सुदृढ़ समाज-व्यवस्था को समझना कठिन नहीं है, जिसके दमखम पर भारत ने न केवल इतिहास के थपेड़ों को सफलतापूर्वक झेलकर एक हजार साल की गुलामी में भी अपने अस्तित्व की रक्षा की, बल्कि स्वयं को एकता के ऐसे प्रबल सूत्र से भी आवद्ध करके रखा, जो उन्हें हमेशा यह अहसास कराता रहा कि मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति एक है। हर तीन वर्ष के अंतराल पर क्रमशः प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में लगनेवाले कुंभ में जाने कब से भारत के कोने-कोने से श्रद्धालु एकत्र होते रहे हैं। उनकी बोली, वेशभूषा, खानपान अलग-अलग रहे हैं, लेकिन सब एक ही विचार और भावना से यहां जुटते रहे कि कभी देव-असुरों द्वारा किये गये समुद्रमंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थीं और इन स्थानों पर उन मुहूर्तों में जाने से अमृत की या मोक्ष की प्राप्ति होती है।

इन कुंभ मेलों का प्रतीक चिह्न (शुभंकर) 'कुंभ' है। 'कुंभ' शब्द अनेकार्थी है जो इस मेले के समस्त प्रयोजनों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। यह शब्द उद्घोषणापूर्वक बताता है कि भारतीय संस्कृति व्यक्ति और विश्व के रिश्तों को 'जल में कुंभ, कुंभ में जल' के रूप में पारिभाषित करती है और पूरी दुनिया को एकात्म भाव से देखते हुए 'वसुधैव कुटुंबकम' का नारा लगाती है। 'कुंभ' कुंभ मेले का ही नहीं, बल्कि हिंदू जीवन पद्धति का एक आवश्यक प्रतीक चिह्न है। हिंदुओं के समस्त पारिवारिक, सामाजिक व धार्मिक कार्यों की शुरुआत 'कलश' स्थापना से ही होती है। विवाह के समय कन्या पक्ष की ओर से महिलाएं सिर पर कुंभ रखकर ही बारात का स्वागत करती हैं, तो अंत्येष्टि यात्रा में भी शव के आगे-आगे एक व्यक्ति कुंभ लेकर ही चलता है।

कुंभ मेलों के आविर्भाव से जुड़ी समुद्र मंथन की कथा भी एक प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी ऋषि ही अमृत कलश को लेकर समुद्र से निकले थे। समस्त रोगों के उपचार का विधान बनानेवाले धन्वंतरी के हाथों में अमृतकलश इसी शाश्वत आकांक्षा को अभिव्यक्ति देता है, "हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल।" अमृत का जो पूर्ण कुंभ संसार, सागर में है, वह हमारे चित्त, समुद्र में भी है, जो बाह्यजगत में है, वह हमारे अंतर्जगत में भी है। विवेक, बुद्धि और तप के द्वारा मन की मथानी से इसका मंथन करके १४ रत्नों के रूप में उल्लिखित समस्त सांसारिक वैभव के साथ-साथ 'मोक्ष' प्राप्त किया जा सकता है।

कोई भी विद्वान दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि कुंभ मेलों की शुरुआत कब हुई थी और इसका स्वरूप क्या वैसा ही था, जैसा कि आज है। वेदों में 'कुंभ' शब्द की चर्चा तो है, लेकिन कुंभ मेलों का उल्लेख उनमें नहीं है। वायुपुराण में 'कुंभ' का वर्णन श्राद्ध के कर्म के संबंध में हुआ है, लेकिन, विष्णुपुराण में सर्वप्रथम कुंभस्नान का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 'कुंभ' स्नान से सहस्रों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसके बाद रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण में समुद्रमंथन की कथा और 'कुंभ' स्नान के माहात्म्य का विशद वर्णन मिलता है। लेकिन इन ग्रंथों से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में से किस स्थान पर इसका प्रथम आयोजन किया गया होगा। पौराणिक परंपरा के अनुसार कुंभ मेला किसी एक पवित्र स्थान पर उस वर्ष होना चाहिए जब सूर्य, चंद्रमा और वृहस्पति का योग कुंभ राशि में होता है और इस ग्रहयोग (वृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में) के बनने पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता रहा है। संभवतः हरिद्वार से ही कुंभ परंपरा का आरंभ हुआ होगा और निश्चित ग्रह-स्थितियों में इसका आयोजन उज्जैन, नासिक, प्रयाग में भी होने लगा (देखिए 'माया' १५ जनवरी)। लेकिन कालांतर में प्रयाग-कुंभ को सर्वाधिक महत्व मिलने लगा, क्योंकि इसके आयोजन के समय विशिष्ट ग्रह योग बनता है। जब सूर्य और चंद्रमा

अनुकरणीय साधु परंपरा: विरक्त साधु

छाया: वसीमुल हक

मकर (नक्षत्र समूह) में तथा वृहस्पति मेष राशि में होते हैं, तो प्रयाग में कुंभ मेला लगता है। यह वह ग्रह-स्थिति होती है, जब हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरी करके करीब १२ वर्षों में फिर यथास्थान अवस्थित हो जाते हैं और अगले १२ वर्षों के समय-चक्र की शुरुआत होती है। भारतवर्ष में अति प्राचीनकाल से ऋषि-मुनियों की विशाल गोष्ठियों की परंपरा रही है। नैमिषारण्य में एक बार साठ हजार ऋषि एकत्र हुए थे और उन्होंने हिंदुओं के विभिन्न कर्मकांडों के जो विधान बनाये थे, आज तक उन्हीं के अनुसार हिंदुओं के सारे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराये जाते हैं और हर कर्मकांड 'एकदा नैमिषारण्य...' में साठ हजार ऋषियों के एकत्र होने के प्रसंग से शुरू होता है। कुंभ आयोजन के साथ कोई परंपरा तो नहीं जुड़ी है, लेकिन हर्षवर्धन के समय हुए कुंभ पर्व के जो उल्लेख मिलते हैं; उनसे स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर महामोक्ष परिषदों का आयोजन होता था, जिनमें शास्त्रों के ज्ञाता सामयिक धार्मिक विषयों पर लंबा शास्त्रार्थ किया करते थे। राजा-महाराजा और धनी-मानी गृहस्थ पांच वर्षों की आय यहां पर दान कर देते थे। देश के कोने-कोने से आये हिंदू ७५ दिनों तक यहां निवास करते थे और संगम-स्नान व दान कर्म के साथ-साथ ऋषि-मुनियों के प्रवचन सुनते थे। इस परंपरा को शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया और कुंभ मेलों का सर्वाधिक प्रचार उन्होंने ही किया था। प्रयाग के पुनीत क्षेत्र में मोक्ष की कामना से प्राण त्यागने की परंपरा भी उस समय विद्यमान थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका लोप होता चला गया। मुसलमानों और अंग्रेजों के शासनकाल में प्रयाग में कुंभ और अर्धकुंभ मेलों का आयोजन होता रहा, जबकि शास्त्रार्थ की परंपरा लुप्त होती चली गयी, लेकिन हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों के धर्मगुरु, शंकराचार्य, मंडलेश्वर और विभिन्न अखाड़े कुंभ मेलों में आते रहे और अपने प्रवचनों और उपदेशों से कल्पवासियों का मार्गदर्शन करते रहे। धनी-मानी गणमान्य लोग और कल्पवासी यहां दान देने आते थे और कुछ लोग तो यहां अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले जाते थे। लेकिन आजादी के बाद कुंभ मेलों का धार्मिक महत्व धीरे-धीरे समाप्त होता गया। आज भी धनी-मानी लोग कुंभ मेले में आते हैं और सरकारी अधिकारी भी कुंभ-व्यवस्था में सहयोग देने आते हैं, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर उनका मकसद अब यहां दान करना नहीं, बल्कि यहां से काफी कुछ कमाकर ले जाना होता है। पहले लोग यहां अर्थ और काम का विसर्जन करके धर्म और मोक्ष की सिद्धि करने आते थे, लेकिन आज तो यहां उनका उद्देश्य सिर्फ अर्थ और काम की सिद्धि करना होता है। इसका फल यह हुआ है कि यहां आनेवाले त्यागी-तपस्वी के रूप में विख्यात अधिकांश धर्माचार्य भी धन के आडंबर से ग्रसित होते चले गये। यही वजह है कि इन धर्मप्रमुखों के मेला क्षेत्र में लगे पंडाल आज जगमगाती धार्मिक दुकानें नजर आने लगे हैं और कुंभ मेले के सारे परिवेश ने आडंबर का रूप ले लिया है। बेशुमार बल्बों से लकदक करते मंडलेश्वरों के पंडाल देखने श्रद्धालु नहीं आते। यह चमक-दमक तो दशहरा-दीवाली और शादी-विवाह के अवसर पर हर व्यक्ति देखता रहता है। घिसे पिटे प्रवचनों और फिल्मी धुनों की चाशनी चढ़े भजन कीर्तन का अनगिनत ध्वनि विस्तारक यंत्रों से निकलता कानफोड़ शोर भी सुनने श्रद्धालु नहीं आते, लेकिन अब उनको यहां मिलता यही है।

लेकिन इस बाजार और चकाचौंध से दूर एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां साधुओं के पारंपरिक एकांत शांत जीवन के दर्शन होते हैं। यह स्थान है झूंसी के बगल में, जहां पेड़ों से आच्छादित ऊंचे-ऊंचे टीले हैं। यहां विरक्त साधुओं की मंडलियां रहती हैं—छोटी-छोटी पुआल की झोंपड़ियां बना कर या १०-१५ फुट लंबी गुफाएं खोद कर वे शांति-साधना करते हैं, चिंतन-मनन करते हैं। यहां इस बार चार मंडलियां थीं—बाबा हजारा सिंह, बाबा वामदेव, बाबा विश्वानंद और बाबा प्रकाशानंद की। विरक्त साधु अपने पास कुछ नहीं रखते और भिक्षा मांग कर खाते हैं। लेकिन हरिद्वार कुंभ से बाबा विश्वानंद और बाबा प्रकाशानंद की मंडलियों ने भक्तों द्वारा चलाये जा रहे अन्नक्षेत्रों में भोजन करना स्वीकार कर लिया है।

इन मंडलियों की भोजन करने की शैली भी मुग्धकारी है। सभी संन्यासी एक कतार में बैठते हैं। पहले से धुले हुए बरतनों को फिर गर्म पानी से धोते हैं और इसके बाद परोसने वाले साधु बहुत ही करीने और फुर्ती से एक-एक व्यंजन परोसते हैं। सारी सामग्री परोसने के बाद गीता के १५वें अध्याय का सस्वर पाठ होता है और शुरू होता है खाना। परोसने-वाले किसी को इंतजार नहीं करने देते और हर वस्तु के साथ राम लगाकर आग्रह करके परोसते हैं। खाना समाप्त होने पर किसी साधु की थाली में जरा-सा अवशिष्ट नहीं रहता। जैसी साफ-सुथरी थालियां परोसी गयी थीं, खाने के बाद वैसी ही नजर आती हैं। खाना समाप्त होने पर रावणकृत शंकर-स्तुति का सस्वर सामूहिक उच्चारण होता है और साधु उठ जाते हैं। इस परंपरा का पालन पहली टोली के खाना खाने के समय होता है। इन साधुओं में कुछ गहन गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं जहां थोड़ी-सी देर घुसने में ही दम घुटने लगता है। लेकिन जब गुफा के अंदर एक साधु को टार्च की रोशनी में देखा, तो उनकी मुखमुद्रा शांत और चेहरे पर तेज था। जो सुख इन विरक्त साधुओं को देखने में मिलता है, वही सुख इनसे बात करने में मिलता है। बाबा वामदेव से जब कुंभ की चर्चा हुई, तो उन्होंने अपनी सधी हुई भाषा में शास्त्रों के उदाहरण के साथ ऐसी बातें कीं, मानो कोई प्रोफेसर बोल रहा हो। इन विरक्त साधुओं की मंडलियों को देखकर जब **'माया'** की टीम चली, तो दिवस का अवसान हो रहा था। संगम के बाद गंगा की संश्लिष्ट धारा पर रक्ताभ चादर बिछी थी। किनारे पर कुछ श्रद्धालु दीपदान कर रहे थे। पीछे विरक्त साधुओं का सुशांत स्थान और सामने प्रकृति की यह छटा, लगता था कुंभ वहां नहीं, जहां बाजार सजा है, बल्कि यहीं है, यहीं है, यहीं है!

—'माया' टीम

कल्पवासी

आस्था किसी की; मौज किसी की

वनवास से भी बदतर: संगम उत्तरी में कल्पवासी

जिस तरह भारत का हालीवुड कही जानेवाली मायावी महानगरी बंबई में एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, तो दूसरी तरफ उनको अंगूठा दिखाती अनगिनत झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, उसी प्रकार संसार के सबसे बड़े धार्मिक मेले 'महाकुंभ-१९८९' में एक तरफ शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों, शाही अखाड़ों तथा सरकारी बाबाओं के कैंप लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर शास्त्री पुल के उत्तर में स्थित संगम उत्तरी, झूसी, अरैल और गंगद्वीप उत्तरी में कल्पवासियों की टेंट (छोलदारी) निर्मित झोंपड़ियां फैली हुई हैं। इन टेंटों में एक महीने तक कल्पवास करनेवाले एक लाख, साठ हजार से अधिक वे तीर्थयात्री हैं, जिनका महत्व किसी महामंडेश्वर, किसी बाबा से तनिक भी कम नहीं है, लेकिन वे उपेक्षित पड़े हैं। गंगा-जमुना की ठंडी रेत पर मोक्ष की कामना करनेवाले कल्पवासियों के नाम पर करोड़ों की गोटियां लाल की जा रही हैं। व्यवस्था के संबंध में मंडलायुक्त रवींद्र गुप्त और मेला प्रभारी जेएन द्विवेद्वी चाहे जितनी लंतरानियां हांकें, लेकिन ठंड से ठिठुरते, मैले कपड़ों में आवृत इन आस्थावान कल्पवासियों की दशा दयनीय है। उन्हें ऐसी जगह पटक दिया गया है, जहां उनके लिए न ठीक से पानी मुहैया है और न शौचालय और न जलावन की लकड़ी। कहीं मेन सड़क पर उनके टैंटों से दूर एक-आध नल लगा दिया गया है, जहां से बेचारे पानी ढोकर लाते हैं। शौचालयों का तो और बुरा हाल है। कहने को तो प्रशासन ने कल्पवासियों के लिए १४४२० कुंतल जलाने की लकड़ी का इंतजाम किया है, लेकिन रीवां से अपनी नतिनी के साथ आये ५० वर्षीय माधव राम का कहना है, "लकड़ी-पुआल तो हमें खुद जुटाना पड़ा, दवाएं तो कुछ मिल भी जाती हैं।"

इसी प्रकार मेला अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने ढाई लाख से भी अधिक राशन कार्ड बनाये हैं, लेकिन कुछ कल्पवासियों ने उलटी ही बात बतायी। बिहार के सीतामढ़ी जिले से १५-१६ बुढ़ियों के साथ आयीं, ५० वर्षीय गायत्री देवी का रोना भी यही है कि दर-दर दौड़ने के बाद भी वे राशन कार्ड बनवाने में सफल न हो सकीं। उनका दुखड़ा था, "बबुआ, हमनीं क कौन सुनता? कौनो तरह मौनी बीत जाये, बस!"

दूसरी ओर पांच सितारा संस्कृति की बानगी लेनी हो, तो आप किसी प्रशासनिक पंडाल में चले जाइये, वहां सारी आधुनिकतम सुविधाएं देखने को मिल जायेंगी। किसी सफेदपोश बाबा के पंडाल में चले जाइए, वहां सहज ही चलते वीडियो, बजते कैसेट के गानों की धुन सुनाई पड़ जायेगी। झाड़-फानूस और कुंकुमवाले ऐसे भी बहुत सारे पंडाल दिख जायेंगे, जिनमें अंग्रेजी गानों की धुनें और विदेशी बालाएं तो मिल जायेंगी, लेकिन भक्त एक भी न मिलेगा, जबकि १४-१४ फुट लंबी और चौड़ी एक-एक छोलदारी में १२ से १७ कल्पवासी रहने को मजबूर हैं। दिन तो ये किसी तरह मेले की चकाचौंध में काट लेते हैं, लेकिन रात में इनके पास गठरी बनने के सिवाय कोई चारा नहीं होता।

ज्ञानपुर (काशी) से अपनी भावज, भयो आदि के साथ आये ६८ वर्षीय रघुनाथ मिश्र जिनके पंडा घंटा-घड़ियाल वाले गंगाराम हैं, ने आंखों में आंसू भरकर कहा, "साहब, न तो हम लोगों के लिए टट्टी है, न पानी, क्या करें? गंगाजी का पानी लाते हैं पीने के लिए। सबसे ज्यादा कष्ट तो हमारी औरतों को है, जिनके लिए परदा करने तक की व्यवस्था नहीं है।" रघुनाथ मिश्र का सिर्फ यही दुख होता कि उनके लिए प्रशासन ने शौच और पानी की व्यवस्था नहीं की है, तो कोई बात नहीं, वे किसी-न-किसी तरह काम चला लेते, क्योंकि वे यहां अपना परलोक सुधारने आये हैं, लेकिन उनकी सबसे मर्मांतक पीड़ा यह है कि उनको संगम पर नहाने को भी नहीं मिलता। 'माया' संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि आपको संगम पर नहाने का दुख नहीं है, तो वे शून्य में खो जाते हैं और कह उठते हैं, "दुख त साहब बहुत हव, लेकिन का करीं, कासे कहीं आपन दुखड़ा? हमार सबसे बड़ा दुख त ई हव कि हम जवना काम (संगम नहाने) से आयल हई, उहै नाहीं कै पावत हई।" वे बताते हैं, "जो अंधेरगर्दी इस साल मची है, वह इसके पहले कभी नहीं देखी थी, जबकि मेरा यह सातवां साल है।" पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव से आये कमलाशंकर जिनके साथ तकरीबन दस लोग कल्पवास करने आये हैं जो कि 'दो तुमड़ी का झंडा' वाले नन्हकऊ पंडे के यजमान हैं, के दुख का तो पारावार ही नहीं। उन्होंने तो बताया, "साहब पहिले काली सड़क पर हम लोगन के जगह मिलत रही, लेकिन हमहन क अबकी कौनो सुनवाई नाहीं बाय। भला हो पंडाजी क, जगह मिल गइल। लेकिन नहइले क बड़ा दुख है। पुलिसवाले जहई नाही देतें। जिद कइले पर मारे-पीटे लगत हैं। हमहन जब चित्रकूट वाले त्यागीजी से अपील कईली, त उ कहनै कि भाई हम का करें?"

दूसरा चेहरा: इन्हीं कष्ट झेलते, बूंद-बूंद पानी और शौच के लिए मारे-मारे फिरते कल्पवासियों के बीच एक सामंती चेहरा भी उभरता है। कहां तो एक ओर मैले-कुचैले पुराने टेंट और उनमें से झांकती भारत की असली तस्वीर और कहां दूसरी तरफ उप्र सरकार के मंत्री श्यामसूरत उपाध्याय की धर्मप्राण पत्नी यानी मंत्राणीजी का टेंट सजा-संवरा, अमलों-कफलों से दुरुस्त। क्या नल, क्या पाखाना! अर्थात सारी सुविधाओं से लैस और चाक-चौबंद। मजे की बात तो यह है कि उनका एक कौड़ी भी खर्च नहीं होना है, जबकि एक आम-कल्पवासी को एक टेंट का ३०० रुपए महीना किराया देना होगा, अपना खाना-पीना, दवा वगैरह सो अलग। पंडे को सीधा (एक वक्त के भोजन का अन्न), दान-दक्षिणा और गऊ दान उसके ऊपर से। लेकिन मंत्रीजी का खर्च तो सरकार ही वहन करेगी। जैसा कि मंत्रीजी के पंडे 'दो तुमड़ी वाले' लक्ष्मी नारायण का कहना है, "मंत्रीजी हमारे ही यजमान हैं। टैंट तो हमीं ने लगाया है, लेकिन उनका खर्चा तो सब सरकार ही देगी।" एक अकेले मंत्रीजी की पत्नी ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई मंत्रियों और अधिकारियों के परिवार हैं, जो सरकारी खर्चे पर कल्पवास और संगम स्नान कर 'पुण्य' लाभ कर रहे हैं।

मेले के एक समीक्षक का तो यहां तक कहना था कि अब के मेले ने वीआईपी रुख ले लिया है। एक तरफ सरकार तीर्थवासियों से कर वसूल रही है, तो दूसरी तरफ दूकानें नीलाम कर उनसे भी कर उगाह रही है। मेला क्षेत्र में जबरदस्त चर्चा है कि स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का तो मेला क्या लगा घर का नक्शा ही बदल गया। रातोरात कलर टीवी, फ्रिज, परदे सब कुछ बदल गये। मेला अधिकारियों को वाहवाही लूटने से ज्यादा मतलब है, कल्पवासियों से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं है। यहां तो ऐसे-ऐसे साधुओं की पूछ है जो लंपट ज्यादा, साधु कम हैं। कहीं एक एकड़ में तांत्रिक चंद्रास्वामी हैं, तो कहीं भूतनाथ? कहीं मुरारीबापू हैं, तो कहीं पायलट बाबा और कहीं धन का भौंडा प्रदर्शन करनेवाले संत ज्ञानेश्वर आदि। ऐसा लगता है कि यह मेला सरकारी जलसा होकर रह गया है। अफसरों के लिए सरकारी खर्चे पर इससे अच्छा पिकनिक स्पाट कहां मिलेगा?

—डा० मुश्ताक अली

कुंभ में स्वयं सेवी संगठन

जो पुण्य सेवा में है, वह स्नान में नहीं

शताब्दी के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव, प्रयाग में आयोजित कुंभ-१९८९, में पहुंचनेवाले अनुमानित एक-सवा करोड़ तीर्थयात्रियों के लिए जहां सरकार ने व्यापक प्रबंध किये हैं, वहीं देश के कोने-कोने से प्रयाग पहुंचे स्वयंसेवी तथा सेवाभावी संगठनों ने भी पहले की तरह इस बार भी तीर्थराज प्रयाग पहुंचनेवालों की सेवा-सहायता का तन-मन-धन से बीड़ा उठा रखा है। स्थिति यह है कि कुंभनगर के लगभग सभी हिस्सों में, विशेषकर, दक्षिण झूंसी स्थित अन्नक्षेत्र और गंगद्वीप उत्तरी व दक्षिणी में, निःशुल्क भोजन एवं चिकित्सकीय सुविधाएं इस तरह से इफ़राद हैं कि अकसर शहर इलाहाबाद के स्थानीय लोगों को मोटर गाड़ियां रोककर परिवार के साथ भंडारों में भोजन करते देखा जाता है। सेवा के भाव से प्रयाग पहुंचे इन संगठनों की नजर में छोटे-बड़े या अपने-पराये का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वे यह मानकर प्रयाग पहुंचे हैं कि जो पुण्य उन्हें श्रद्धालुओं, साधु-संन्यासियों की सेवा से मिलेगा, शायद संगम में डुबकी लगाने से नहीं। 'माया' ने अपने सप्ताहभर के अनवरत दौरों के बाद पाया कि पंजाबवासियों (जिनमें सिख-हिंदू दोनों शामिल पाये गये, किंतु सिख समाज के लोग ज्यादा थे) और मारवाड़ी समाज के लोगों में जो सेवाभाव है और जिस उदारता के साथ वे तीर्थयात्रियों की सेवा में जुटे हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यही हाल चिकित्सकीय सुविधा का भी है। जहां कहीं किसी को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़े, नज़र उठाते ही धर्मार्थ चिकित्सालयों के बैनर दिखायी पड़ जायेंगे जहां मुस्तैदी के साथ सेवाभाव से डाक्टर २४ घंटे मौजूद होते हैं।

सेवाभावी संगठन: इसके बरअक्स कुंभक्षेत्र में ऐसे सेवाभावी संगठनों की भी कमी नहीं है जहां कार्यक्रम के अनुसार कथा-कीर्तन और प्रवचन का दौर न चलता रहता हो। जहां एक ओर 'ऐवरीह्वेअर इज कृष्णा, ओनली सोर्स इज कृष्णा' की रट लगाते हुए 'इस्कान' जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के कृष्णाभक्त प्रसाद बांटते हुए मिलेंगे, वहीं सड़कों, पौंटून पुलों और रेतीले मैदानों में दुलियाजान (असम) से आये ब्रजभूषण सिंह (पौंटून पुल ७ के पास) जाड़े से थरथराते-लड़खड़ाते वृद्ध यात्रियों, साधुओं को सहारा देते हुए 'माया' से कहते हैं, "यदि कुंभ क्षेत्र में समाजसेवी, स्वयंसेवी और सेवाभावी संगठनों द्वारा तीर्थयात्रियों की सेवा-सहायता आधी-अधूरी की जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार संगठन नहीं, बल्कि प्रशासन है, क्योंकि संगठनों को इन्हीं का सहयोग करना है और इन्हीं से अपने काम की सनद पानी है।" यह कहकर ब्रजभूषण उन संस्थाओं की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने सेवा के नाम पर धनउगाही या अपने परिजनों की सेवा-सुविधा के साधन जुटाये हैं। निस्संदेह ऐसे भी संगठन मेला क्षेत्र में हैं, जो ३० जनवरी तक पूरी तरह निष्क्रिय रहे और उनके कैंप उजाड़ पड़े रहे।

स्नान से महान सेवा: मारिसो का सेवा-शिविर

'माया' ने सात दिनों के अभियान में जिन लगभग पचास संगठनों से संपर्क स्थापित किया, उनमें से अधिकांश सेवा में व्यस्त पाये गये। संगठनों की सेवा के आधार पर उन्हें प्रमुख रूप से तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है:

१-भोजन सहित आवास (सिर्फ भोजन तथा चिकित्सा सुविधा) वाले संगठन

२-मात्र चिकित्सा सेवा देनेवाले संगठन

३-सहायता-सेवा (जैसे भूले-भटकों को मंजिल तक पहुंचाने) में व्यस्त संगठन।

ऐसे संगठन प्रमुख रूप से गंगद्वीप उत्तरी तथा झूंसी दक्षिणी अन्न क्षेत्र में सेवारत पाये गये। इनमें गंगद्वीप उत्तरी में स्थित दयालू सत्संग मंडल नैरोबी, भारत रिलीफ सोसायटी तथा अन्न क्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र, पंजाब सिंध अन्न क्षेत्र, जयराम आश्रम अन्नक्षेत्र, झूलेलाल भंडार आदि प्रमुख हैं। गंगद्वीप उत्तरी में स्थित दयालू सत्संग मंडल नैरोबी के सेवकों का दावा है कि वे प्रतिदिन ४०-५० हजार लोगों को भोजन करा रहे हैं तथा इस कुंभ में एक करोड़ रुपए भंडारे पर खर्च करने का उनका लक्ष्य है। 'माया' द्वारा यह पूछे जाने पर कि संस्था का आर्थिक स्रोत क्या है? संस्था के अध्यक्ष एमजी शर्मा बोले, "यह सब ब्रह्मलीन श्री स्वामी दयाल पुरीजी के अनुयायियों की कृपा है।" इसके अतिरिक्त अन्य सभी संगठनों द्वारा इस कुंभ में बीस से पच्चीस लाख रुपए सेवा-सहायता पर खर्च करने का लक्ष्य बनाया गया है। 'माया' ने विस्तृत खोजबीन के बाद पाया कि इनमें से लगभग सभी ने आवास हेतु १५० से ४५० कैंप लगाये हैं जिनमें ठहरनेवाले यात्रियों से ३०० रुपए प्रतिमाह से ३५०० रुपए प्रतिमाह तक किराया लिया जा रहा है जिसे संस्था के संयोजक दान कहकर पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क साधु-सेवा के रूप में सुबह के नाश्ते और दिन के भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। इस निःशुल्क भोजन-सेवा के समय प्रतिदिन प्रत्येक उल्लिखित संस्था द्वारा अब तक १५०० से २००० लोगों को नाश्ता एवं भोजन कराया गया। संस्था के संयोजकों का दावा था कि मौनी अमावस्या तक उनकी संख्या दो से ढाई हजार के बीच पहुंच जायेगी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त संस्थाओं के चिकित्सा संभाग के डाक्टरों का दावा यह रहा कि प्रतिदिन वे ५०० से ८०० लोगों को निःशुल्क दवा देते हैं। यही नहीं, इन संस्थाओं ने इमरजेंसी केस के लिए अपने कैंपों में मरीजों को भरती करने की व्यवस्था भी कर रखी है, जहां इमरजेंसी में इस्तेमाल में लाये जानेवाले चिकित्सकीय उपकरण भी देखे गये। भारत रिलीफ सोसायटी के संयोजक चुन्नीलाल सोमानी ने 'माया' को बताया, "सोसायटी के तीन चल चिकित्सालय भी मेला क्षेत्र में सेवारत हैं, जो प्रतिदिन २५० से ३०० लोगों को चिकित्सा सुविधा देते हैं।" इसी तरह जयराम आश्रम द्वारा भी चल चिकित्सालयों की व्यवस्था की गयी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा सुलभ कराने का कार्य करनेवाली रेड क्रास सोसायटी भी अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी तीर्थयात्रियों की सेवा में जुटी हुई है। गंगद्वीप स्थित प्रमुख कैंप में ड्यूटी पर तैनात डाक्टर एमजी शाह ने 'माया' को बताया, "साहब, हमारा काम तो केवल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना है, किंतु मरीजों का कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा। मजबूर होकर हमने रोगियों को दवाई बांटनी भी शुरू कर दी है। किंतु अकसर हम चाहते हुए भी अपनी सुविधा लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। उसका कारण यह है कि कुंभक्षेत्र में

गाड़ियों को किस दिन किस रास्ते से किधर जाना है, यह निश्चित नहीं है। प्रतिदिन हमारा आधे से ज्यादा समय तो ट्रैफिक व्यवस्था समझने में ही चला जाता है।" उन्होंने आगे बताया, "हमारे कार्यकर्ताओं को बेवजह पुलिस प्रताड़ित करती है। इसके लिए हमने कमिश्नर से शिकायत भी की है। न जाने क्या कारण है कि इस बार हमारे सेवाभाव को कम करके देखा जा रहा है। हमें सचमुच इस बात का बहुत अफसोस है।"

निरंकारी मिशन अकेली ऐसी संस्था है जिसने आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथी चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है और जनवरी के प्रथम सप्ताह से फरवरी के प्रथम सप्ताह तक लगभग ६,००० लोगों की सेवा की है। अधिकतर धर्मार्थ चिकित्सालय गंगद्वीप और कल्पवासी क्षेत्र में हैं। संगम उत्तरी क्षेत्र में एक ही मार्ग पर लगभग आधा दर्जन से अधिक औषधालय हैं। इनके अतिरिक्त जिला होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और लायंस क्लब आफ इलाहाबाद के संयुक्त तत्वावधान में भी धर्मार्थ चिकित्सालय डा० टी सहाय के निर्देशन में ८ जनवरी से चल रहा है जिसमें २ फरवरी तक ६ हजार से अधिक रोगियों को देखा जा चुका है। इसी तरह संगम दक्षिणी में स्थित मोतीलाल नेहरू चल चिकित्सालय के कैंप में संपर्क करने से पता चला कि इस संस्था की ओर से संपूर्ण कुंभ नगर में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार चल चिकित्सालयों की व्यवस्था की गयी है जो २४ घंटे मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कुंभक्षेत्र में ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के कैंप भी पर्याप्त हैं जिनके स्वयंसेवक तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शन एवं सहायता हेतु तत्पर दिखायी पड़े। ऐसे स्वयंसेवकों में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं का नाम उल्लेखनीय है जिन्हें कहीं न कहीं किसी सड़क या पीपा पुल के पास तीर्थयात्रियों की सहायता करते हुए देखा जा सकता है।भूले-भटकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना तथा अत्यधिक कमजोर तीर्थयात्रियों को सहारा देकर सड़क पार कराना आदि इनकी सेवाओं के प्रमुख उदाहरण हैं।

इनके अतिरिक्त 'माया' को संगम दक्षिणी और संगम उत्तरी क्षेत्रों में स्वयंसेवी और सेवाभावी संगठनों के २२ शिविर और मिले जिनमें से अधिकांश में कमोबेश सेवा-सहायता का कार्य होता पाया गया। इन संगठनों और इनके कार्यों से अगर कोई राजनीतिक अर्थ निकाला जाये, तो कोई भी निःसंकोच भाव से कह सकता है कि प्रयाग महाकुंभ के मेले में राजीव गांधी की कांग्रेस जीत गयी है और विपक्ष का कोई वजूद बाकी नहीं रह गया है। —वशिष्ठ, तारिक खान

तंत्र चंद्रा स्वामी की दृष्टि में

इस बार प्रयाग कुंभ में देश-विदेश में चर्चित और विवादास्पद धर्मगुरु चंद्रा स्वामी भी पहुंचे। उनके बारे में यह प्रचारित है कि उन्होंने अपनी तंत्र शक्ति से देश-विदेश के शक्तिशाली लोगों को अपना अनुयायी बना रखा है। मेला क्षेत्र में शंकराचार्य मार्ग पर स्थित उनके पंडाल में 'माया' ने, उनसे विशेष साक्षात्कार के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा की, लेकिन खास तौर पर जानना चाहा कि उनकी दृष्टि में तंत्र क्या है? उन्होंने जो उत्तर दिया उसे अविकल यहां प्रकाशित किया जा रहा है:

"जैसे साइंस के अंदर टेक्नोलाजी है, कई स्पेयर पार्ट्स, कई मशीनें जोड़ कर एक नयी मशीन तैयार की जाती है। तो तंत्र स्प्रिच्युअल साइंस का, साइंस आफ द सोल की एक टेक्नोलाजी है। आपने देखा होगा कि आजकल साइंस ने कितना विकास किया है। उस साइंस का सेंट्रल पार्ट क्या है, इलेक्ट्रीसिटी-ऊर्जा या और कोई तो नहीं है। उसी तरह हमारा जो शरीर है, यह पंच तत्व से बना हुआ है। उसमें अग्नि भी एक है। साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ऊर्जा की शक्ति प्राप्त की। जो साधक है वह पंच तत्व पर संयम के द्वारा अग्नि शक्ति प्राप्त करके नयी ऊर्जा, नयी चेतना को जागृत करता है। इसी प्रक्रिया को तंत्र कहा है।"

स्वामी मृत्युंजय द्वारा तंत्र की व्याख्या

श्री आनंद वन समाधि, हरिद्वार में साधनारत महामानव स्वामी मृत्युंजय आणविक भौतिकी के विद्वान के साथ-साथ संपूर्ण निगम-आगम मर्मज्ञ भी हैं। उन्होंने तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर तंत्र के सार पर यों प्रकाश डाला:

तनु-विस्तारे = उकारो लोप: तनु-
उ = तन् + त्र = तंत्र
परिभाष: तनोति त्रायते स: तंत्र:

तन का अर्थ होता है विस्तार, अनेकता, विविधता विभ्रम आदि। जो उपाय इस विस्तार या अनेकत्व विभ्रमादि से त्राण दिलाये, उसे तंत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में संसार की तीन मूल ऊर्जाओं (सत, रज और तम या इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा और विद्युत् चुंबकीय ऊर्जा) के विस्तार के कारण उत्पन्न वैषम्य से छुटकारा दिलाये वह तंत्र है।

वैषम्य से मुक्ति के अनेक उपाय हैं जो तंत्र की विभिन्न शाखाओं में विभक्त हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को चमत्कृत करना या हानि पहुंचाने का उपाय करना षड्यंत्र की कोटि में आता है।

◆

प्रयाग के पंडे

प्रयाग के संगम क्षेत्र में १४ जनवरी मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए विश्व के विशालतम कुंभ मेले में कहां तो अनुमान था कि एक-दो करोड़ से अधिक लोगों की आवक-जावक रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामान्य माघ मेलों से भी कम संख्या में लोगों के आने के कारण न केवल उन दुकानदारों को गहरा झटका लगा है, जिन्होंने ऊंची बोलियां बोलकर महंगी कीमत में मेला क्षेत्र में अपनी दुकानें लगायीं, बल्कि वे तीर्थपुरोहित भी हताश हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में यजमानों के आने की आशा में भारी तैयारियां की थीं और मेला प्रशासन से अधिक जमीन तथा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक कटुतापूर्ण संघर्ष चलाया था। यहां के तीर्थ पुरोहितों का एक जमाने में ऐसा ठसका था कि उन्होंने भगवान राम को ब्राह्मण रावण का वध करने के कारण ब्रह्म हत्या का दोषी बताकर उनसे दान लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने देश निकाला सहन किया था, लेकिन सम्राट अकबर से सोने के हाथी तक का दान नहीं लिया था। इन्हीं तीर्थ पुरोहितों के आश्रय और मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष यहां माघ मेले, हर छह वर्ष में अर्धकुंभ और हर १२ वर्ष में महाकुंभ आयोजित होते रहे हैं और यहां आनेवाले हर कल्पवासी, धर्मगुरु, शंकराचार्य से लेकर भिखारी तक का कोई-न-कोई तीर्थ पुरोहित हुआ करता है। कोई जमाना था, जब तीर्थपुरोहित माघ व कुंभ मेले में आनेवाले अपने यजमानों की निःशुल्क भोजन व्यवस्था किया करते थे। एक कुंभ में तो उन्होंने एक साथ एक हजार आदमी एक भोजनालय में खा सकें—ऐसे सौ भोजनालय ही बनवा दिये थे। लेकिन आज वे तीर्थपुरोहित न केवल उपेक्षित हैं, बल्कि अनेक तीर्थ पुरोहित परिवार तो विपन्न स्थिति में आ चुके हैं। एक तीर्थ पुरोहित का कहना है, "हमने इस महाकुंभ से बड़ी उम्मीदें लगायी थीं, लेकिन लोग इतने कम आये हैं कि तंबू-कनात का खर्चा तक निकालना मुश्किल हो जायेगा और तीर्थपुरोहितों के पहले से विपन्न हुए अनेक परिवार तो अपना धंधा तक बदलने पर मजबूर हो जायेंगे।"

इतिहास : किसी वक्त प्रयाग में पंडों के १४८४ खानदान थे, अब ५५० ही बचे हैं। इनका इतिहास भी उतना ही पुराना है, जितना की तीर्थ स्थानों का। तीर्थ स्थानों की यात्रा हिंदू जीवनचर्या का एक आवश्यक अंग है और लोकमान्यता के अनुसार हर हिंदू को अपने जीवन में एक-न-एक बार भारत के तीर्थों की यात्रा करनी जरूरी होती है, क्योंकि इसके बिना पापों का प्रायश्चित और मोक्ष प्रदान करने में सक्षम पुण्य लाभ की कल्पना नहीं की जा सकती। हर तीर्थ स्थल पर तीर्थ पुरोहित होते हैं और वे ही तीर्थयात्रियों से विभिन्न धार्मिक कर्मकांड कराते हैं और इसके बदले में तीर्थयात्रियों से उन्हें जो दान मिलता है, उसी से उनकी जीविका चलती है। भगवान राम से जब प्रयाग के तीर्थ पुरोहितों ने दान लेने से इनकार कर दिया, तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने अपने परिवार के एक व्यक्ति को ब्रह्महत्या के प्रायश्चित स्वरूप राम से आवश्यक कर्मकांड कराने के लिए प्रयाग भेजा था। वशिष्ठ द्वारा प्रेषित उक्त व्यक्ति की संतानें (अमरनाथ गोकुल प्रसाद मिश्र, जयनारायण व लक्ष्मण प्रसाद मिश्र) आज भी नयी बस्ती कीडगंज में निवास करती हैं। सम्राट अकबर ने प्रयाग के किले की दीवार बनाने के लिए एक ब्राह्मण और दो हाथियों की बलि दी थी। (इनकी समाधि अब भी वहां मौजूद है), लेकिन यहां के तीर्थपुरोहितों द्वारा अकबर से दान लेने से इनकार करने पर अकबर ने उन्हें यहां से निर्वासित कर दिया था। ये तीर्थपुरोहित तब महाराजा रीवां की रियासत में चले गये, लेकिन बंगाल-विजय से लौटते हुए राजा मानसिंह ने रीवां नरेश के आग्रह पर अकबर ने इन्हें माफीनामा दिलाया था जो पंचभइया प्रयागवाल के यहां आज भी सुरक्षित है। जहांगीर और औरंगजेब के समय में भी तीर्थपुरोहितों का प्रयाग में वर्चस्व कायम रहा था। आगरा किले से भागकर शिवाजी दारागंज के एक तीर्थपुरोहित के यहां रुके थे और यहीं अपने पुत्र संभाजी से उनकी भेंट हुई थी। १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी इन तीर्थपुरोहितों ने मंहगांव के मुसलमानों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था और महारानी लक्ष्मीबाई को भी एक पंडे के यहां शरण मिली थी। तीर्थपुरोहितों की इस विप्लवी भूमिका से चिढ़कर अंग्रेजों ने १८५७ में दारागंज के एक हिस्से को ही तोप से उड़वा दिया था।

कार्य-प्रक्रिया : तीर्थपुरोहितों का अपना-अपना क्षेत्र बंटा रहता है। उनके अपने अलग-अलग रंग-रूप और आकार के झण्डे होते हैं और हर पंडे का अपना एक अलग निशान होता है, हर पंडा एक विशाल बही खाता अपने पास रखता है, जिसमें वह तीर्थयात्रा के लिए अपने यहां आनेवाले हर तीर्थयात्री का नाम-पता पीढ़ियों से लिखता आ रहा है। इसी बही खाते में अपने पूर्वजों के नाम-पते देखकर ही तीर्थयात्री यह तय कर पाते हैं कि उनके इलाके का पंडा कौन है? तीर्थयात्रियों को लाने और उनका कर्मकांड कराने के लिए इन पंडों के अपने एजेंट नौकर और कर्मचारी भी होते हैं। अब तो घाट अथवा संगम के किनारे चौकी लगाकर बैठनेवाले कुछ 'घाटिये' और नौका में कोई प्रतिमा रखकर इधर-उधर घूमते हुए स्नान करनेवालों से पूजन करानेवाले कुछ 'गोसाईं' भी तीर्थपुरोहितों की तरह दान-दक्षिणा लेने लगे। कुछ तीर्थपुरोहितों ने भुजबल से अपना वर्चस्व कायम किया जिसके कारण तीर्थयात्री अपने क्षेत्र के पंडों तक नहीं पहुंच पाते थे और दूसरे ही पंडे उनसे दान-दक्षिणा ले लेते थे। इससे अनेक पंडों की आर्थिक दशा सुधरी, तो बहुत सारे पंडे दरिद्र होते चले गये।

दरअसल हिंदू समाज का वह आर्थिक ढांचा टूट चुका है जिसमें तीर्थपुरोहित ही तीर्थ स्नानों के सर्वेसर्वा हुआ करते थे।

सन १९०६ में पंडित मदन मोहन मालवीय ने तीर्थपुरोहितों की एक संस्था 'प्रयागवाल सभा' की स्थापना की। पं० वसंत लाल शर्मा, पं० पशुपतिनाथ शर्मा, पं० कोटेश्वरनाथ मिश्र, पं० ओंकारनाथ अजैन, पं० माधोलाल, पं० त्रिभुवन नाथ, पं० राम प्रसाद मिश्र और पं० शेष नारायण सोकहा के प्रयास से तीर्थपुरोहितों के कार्य को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा का धीरे-धीरे ह्रास होता चला गया।

आज पंडों के रूप में विख्यात ये तीर्थपुरोहित तीर्थयात्रियों को लूटने के लिए बदनाम हैं। लेकिन प्रयाग वाल सभा के नारायण प्रसाद शर्मा का कहना है, "अपराधी प्रवृत्ति के लोग हर समुदाय में हैं, दरअसल, अपराधी ही पंडे बनकर तीर्थयात्रियों को लूटते हैं। कोई पंडा अपने तीर्थयात्री को नहीं लूट सकता, क्योंकि इससे तो उसकी सारी यजमानी ही समाप्त हो जायेगी, यदि एक भी तीर्थयात्री लुटता है, तो वह तीर्थपुरोहित उसके इलाके में कैसे जा पायेगा?" लेकिन यह तथ्य है कि तीर्थपुरोहितों की साख दिन-ब-दिन खतम होती जा रही है। बढ़ती शिक्षा और धर्म के प्रति घटती आस्था ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने सुनियोजित ढंग से पंडों के वर्चस्व को समाप्त करने के उपक्रम किये। क्योंकि उनकी नजर में ये तीर्थपुरोहित प्रत्येक हिंदू के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। उन्होंने १९३८ व १९४० में जो मेला एक्ट कुंभ और अर्धकुंभों की व्यवस्था के लिए बनाया गया, उनमें तीर्थपुरोहितों को व्यवसायी माना गया है। न केवल विभिन्न दान लेने के लिए उन पर कर लगाये गये, बल्कि कल्पवासियों के लिए इन्हें जो जमीनें मेलाक्षेत्र में दी जाती रहीं, उनका भी किराया उनसे वसूला जाता है।

आजादी के बाद हुए अर्धकुंभों और महाकुंभों में भी सरकार का नजरिया उनके प्रति वही रहा, जो अंग्रेजों का था। कुंभ-१९८९ में २-३ लाख लोग मेला क्षेत्र में हैं, लेकिन इनमें उन लोगों की संख्या बेहद कम है, जो तीर्थपुरोहितों को दान-दक्षिणा देकर मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने में आस्था रखते हैं। दरअसल हिंदूसमाज का वह धार्मिक ढांचा टूट चुका है जिसमें तीर्थपुरोहित ही तीर्थ स्थानों के सर्वेसर्वा हुआ करते थे। यह सोचना अब प्रयाग के पंडों का काम है कि इस बदले परिवेश में वे अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पायेंगे?

—विनोद मिश्र

बाबा लामीटारे

विचित्र साधु

अगर गहन अध्ययन किया जाये, तो साधु समाज में बड़ी विचित्रताएं देखने को मिलती हैं। पहली विचित्रता तो साधु समाज के कुछ नामों की ही है। बड़े-बड़े विचित्र नाम हैं, साधुओं के। खटपटिया बाबा, लट्ठमार दास, हाण्डीवाले बाबा, बाबा धर्मधक्का, टुनटुनी महाराज, धुरन्धर दास, मुच्छन्दर नाथ, पगला बाबा, भूतनाथ मूर्खानन्द, चतुरमुनि, लटकन नाथ, भोण्डे बाबा, टुकड़नाथ आदि विचित्र नाम तो हैं ही, साथ ही कुछ साधुओं के अश्लील नाम भी हैं। हरिद्वार के चार गुरुभाई साधुओं के नाम तो और भी विचित्र हैं। एक ही गुरु के इन शिष्यों के नाम हैं—गुण्डा स्वामी, मुछमुण्डा स्वामी, टुण्डा स्वामी और मुसटण्डा स्वामी।

ओम बाबा : नामों की विचित्रता को छोड़िये, कई साधुओं के काम और उनकी दैनिक चर्या भी बड़ी विचित्र होती है। ओम बाबा को ही लीजिए। हर समय कुछ-न-कुछ बुदबुदाते रहते हैं। त्याग-तपस्या में उनका कोई सानी नहीं। विद्वान भी हैं। हंसते हैं, तो खूब हंसते हैं। लेकिन मौका पड़े, तो रो भी पड़ते हैं। महामानव स्वामी प्रेमानन्दजी मृत्युंजय के बड़े स्नेही हैं। दोनों में खूब मजाक होता है। शास्त्रार्थ भी। ओमबाबा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने तपोबल से एक बार काया-कल्प कर चुके हैं। इस बात में क्या सचाई है, यह तो नहीं मालूम, पर इतना अवश्य है कि ओमबाबा और बहती धार में कोई फर्क नहीं। वह एक बार कहीं निकल जायें, तो वर्षों तक उनके दर्शन नहीं होते।

ओमबाबा सनकी नहीं हैं, फिर भी उनकी सनक का कोई पता नहीं। स्नेह-प्यार से बातें करते-करते कब सोटा उठा लें या गालियां देने लगें, कोई भरोसा नहीं। बातें करते-करते या प्रवचन करते हुए बीच में ही कब उठकर चले जायें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओमबाबा ने आज तक अपना कोई भी स्थान नही बनाया है। वे एक जगह कभी नही ठहरते। मौज आयी, तो नाचने भी लगते हैं।

लामीटारे : देवीभक्त लामीटारे उर्फ बाबा धर्मधक्का का व्यक्तित्व अन्य साधुओं से एकदम अलग है। साधु के साथ-साथ वे तांत्रिक भी हैं। साथ ही आध्यात्मिक रहस्यों के जानकार और विद्वान भी। नेपाल में जन्मे बाबा धर्मधक्का को देश भर के सभी बड़े और तपस्वी साधु जानते हैं। साधु-संतों के जीवन-चरित्रों पर वे जब तक पुस्तकें लिखते रहते हैं, पुस्तकों की सामग्री जुटाने के लिए वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमते रहते हैं—शहरी साधुओं में भी और वन प्रांतों और हिमशिखरों पर रहनेवाले साधुओं में भी। बाबा धर्मधक्का ने अब तक कई पुस्तकें लिखी हैं।

देवीभक्त लामीटारे उर्फ धर्मधक्का की जिंदगी मात्र एक थैले के सहारे चलती है। उसी थैले में वह आवश्यकता की हर वस्तु और लेखन-सामग्री रखते हैं। थैला हर समय उनके कंधे पर झूलता रहता है। बाबा धर्मधक्का बड़े विचित्र स्वभाव के हैं। पर जब सही मूड में हों, तो उनकी विद्वतापूर्ण बातें आश्चर्य में डाल देती हैं। उनका जीवन साधु समाज को समर्पित है।

बाल गोविंददास : अयोध्यापुरी से आये ५५ वर्षीय वैष्णव वैरागी साधु बाल गोविंद दासजी अपने आप में विचित्र व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वे पिछले बारह वर्षों से अपने कंधे पर कामधेनु (गाय नहीं) टांगे हुए हैं। यह कामधेनु उनके कंधे से कभी नहीं उतरती। कामधेनु में ही वे अपनी आवश्यकता की हर चीज रखते हैं। कोई दान दक्षिणा देता है, तो वह भी कामधेनु में ही डलवाते हैं। स्वामी बाल गोविंददास कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरते।

नेपाल के काठमाण्डु क्षेत्र से आये साधु अजंनगिरि मात्र ढाई फुट के हैं। वे कुंभ नहाने एक माह पहले इलाहाबाद आये हैं। अंजनगिरि की शारीरिक विचित्रता के साथ एक विचित्रता यह है कि वे हर समय एक डमरू अपने साथ रखते हैं और उसे बजाते रहते हैं। अंजनगिरि मात्र एक लंगोटी में रहते हैं।

६० वर्षीय वैष्णव साधु बाबा रामदास एटा से कुंभ नहाने आये हैं। उनका कद मात्र साढ़े तीन फुट है। बाबा रामदास ने तीस वर्ष पूर्व संन्यास लिया था। बाबा रामदास की विचित्रता यह है कि वे हर बात में 'राम' शब्द जोड़कर बात करते हैं और हर पांच मिनट बाद उनके मुंह से राम शब्द निकलता रहता है। जगरावां लुधियाना से कुंभनगर आये स्वामी अमरजीत हरि निर्मलपंथी साधु हैं। अपने गुरु स्वामी मेहर सिंहजी के नाम पर वे छत्तनाग के पास विरक्तों के लिए अन्नक्षेत्र चला रहे हैं। स्वामी अमरजीत हरि की विशेषता यह है कि स्वयं भिक्षा करते हैं और गरीबों और संतों की सेवा करते हैं। उन्होंने हरिद्वार कुंभ के बाद से भिक्षा कर के जो एकत्र किया है, वे इस कुंभ में समाप्त कर देंगे और फिर अगले कुंभ की तैयारी। अपने अन्नक्षेत्र में वह भोजन के साथ संतों को कम्बल और जूते भी बांटते हैं। उनके अन्नक्षेत्र में प्रतिदिन २००० लोग भोजन करते हैं।

—पु० पु०

महर्षि, महायोगी और महामानव

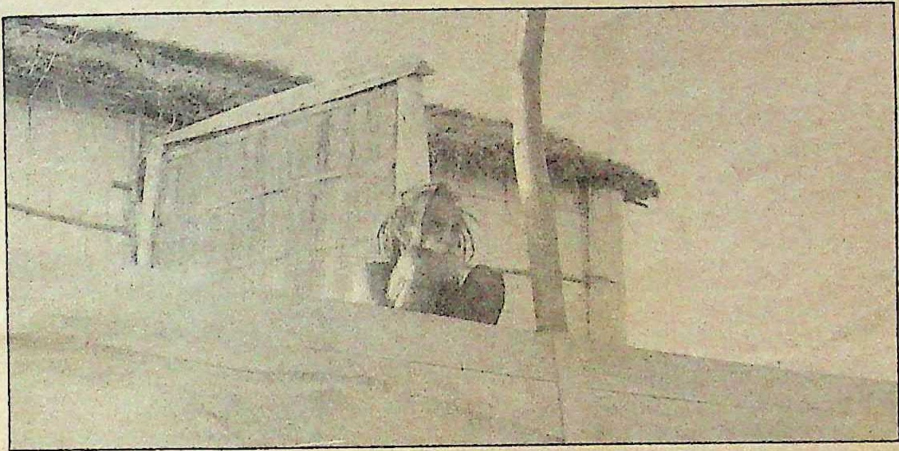

देवरहा बाबा

मीलों तक फैले कुंभ नगर में जहां कुछ बड़े संतों ने अपनी सत्ता शक्ति और धन का खुला प्रदर्शन करके बड़े-बड़े मंच, पंडाल और द्वार सजाकर अपने वैभव का परिचय दिया है, वहीं कुछ ऐसे साधु भी गंगा तट पर आये हैं, जो केवल नाम के ही बड़े नहीं, बल्कि कर्मयोगी भी हैं और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी जाने जाते हैं। यह अलग बात है कि इन महान और तपेश्वर संतों के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं। लेकिन विवादों के बारे में कहा जाता है कि इनके पीछे उनके उन विरोधियों के हाथ हैं जो उनकी प्रसिद्धि से चिढ़ते हैं।

देवरहा बाबा: गंगा के उस पार मेला क्षेत्र से लगभग दो कि०मी० उत्तर में चांदी सी चमकती रेत में गंगा किनारे देवरहा बाबा का मचान बना है। मचान के ऊपर फूस की कुटिया। बाबा के मचान तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार ने लोहे की चादरों की सड़क बनायी है, ताकि वाहन आदि वहां तक पहुंच सकें। विद्युत सुविधा भी मुहैया करायी गयी है। देवरहा बाबा के दर्शनार्थ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। मोटरकारों वाले भी और पैदल भी। बाबा अधिकांशत: अपनी कुटिया में ही रहते हैं। बाहर उनके भक्तगण उनकी महिमा आरती और राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। ज्यों-ज्यों दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों सामूहिक ध्वनि तेज होती रहती है। जब हजार-पांच सौ लोग एकत्र हो जाते हैं, तो बाबा कुटिया के बाहर आकर दर्शन देते हैं। थोड़ा-बहुत उपदेश भी।

देवरहा बाबा प्रतिदिन सुबह चार बजे मंच से उतर कर गंगा स्नान करते हैं और फिर कुटी में चले जाते हैं। उसके बाद वह फिर चौबीस घंटे बाद स्नान के लिए ही मंच से नीचे आते हैं।

देवरहा बाबा की उम्र के बारे में काफी विवाद है। कोई उन्हें एक हजार साल का बताता है, कोई पांच सौ साल का और अस्सी नब्बे साल का। कहते हैं—बाबा ब्रह्मलीन हैं। इसे तूरिया अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद योगी की ऐच्छिक मृत्यु होती है। वह अगर न चाहें तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। देवरहा बाबा का मंत्र है—

> ऊं कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने।
> प्रणत: क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो:
> नम:।।

देवरहा बाबा जिले के मईल गांव के पास सरयू नदी के तट पर मचान पर रहते हैं। वहां भी उनकी वही दिनचर्या रहती है। उनका जीवन वास्तव में बहुत ही रहस्यमय है। उनकी जिंदगी की तहों को टटोलना और समझना बहुत मुश्किल है। पं० जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डा० राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, डा० सम्पूर्णानंद जैसे राजयोगी मनीषियों ने उनकी चरणरज शिरोधार्य की थी।

सन १९३१ में जब देवरहा बाबा इलाहाबाद में गंगा किनारे रह रहे थे, तो पं० मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय पं० जवाहर लाल नेहरू को साथ लेकर उनके पास गये थे। बाबा ने जवाहर लाल नेहरू को देखते ही कहा था, 'यह विश्वविख्यात नेता बनेगा।" प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पं० जवाहर लाल नेहरू उनका आशीर्वाद लेने गये थे। स्व० प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीं भी दो बार देवरहा बाबा का आशीर्वाद लेने मईल गांव गयी थीं। पं० जगन्नाथ मिश्र, वीर बहादुर सिंह, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण और अनेक जानेमाने नेता भी देवरहा बाबा की शरण में जा चुके हैं। सन १९५४ में प्रयाग के कुंभ में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने देवरहा बाबा के चरण स्वयं धोकर चरणामृत पान किया था और बाबा का आशीर्वाद लिया था। सरदार बल्लभ भाई पटेल और पं० जवाहर लाल नेहरू एक बार साथ-साथ भी देवरहा बाबा का आशीर्वाद लेने गयें थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपराज्यपाल डा० एम चन्ना रेड्डी अपनी पत्नी के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने मईल गये थे और अपने सिर पर बाबा का पैर रखकर फोटो खिचाया था, जो वर्षों तक राजभवन में लगा रहा।

देवरहा बाबा को कई आध्यात्मिक सिद्धियों का स्वामी बताया जाता है। संभवत: यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े-बड़े मंत्री और अधिकारी बाबा के भक्त बने रहते हैं। देवरहा बाबा से कुछ विवाद भी जुड़े हैं। लेकिन उनके प्रति हर वर्ग के लोगों की श्रद्धा और आस्था के सामने उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर भी कुछ बातें ऐसी जरूर हैं, जो कुछ सोचने को मजबूर करती हैं। जैसे देवरहा बाबा के सेवकों द्वारा अपनी छपायी महंगी पुस्तक को बाबा के आशीर्वचन के नाम पर बेचना, चंदा करना और श्रद्धालु दर्शकों की उपेक्षा करके महत्वपूर्ण लोगों को अविलम्ब दर्शन करा देना। हो सकता है, यह सब बाबा के सेवकों द्वारा बनाया गया चक्र हो, जिससे बाबा जी अनभिज्ञ हों? वैसे भी योगीराज को इतनी धन-सम्पदा का क्या करना है?

पायलट बाबा

महायोगी पायलट बाबा: कर्मयोग के बल पर विश्वशांति के लिए प्रयास करनेवाले पायलट बाबा भी कुंभ नगर पधारे हैं। उन्हें भारत के बड़े साधुओं में गिना जाता है। पायलट बाबा अब तक ३७ बार ५ दिन से लेकर ३३ दिन तक की समाधियां, जापान और भारत के अनेक नगरों में लगा चुके हैं। समाधि में प्रवेश करते ही पायलट बाबा का हृदय स्पंदन बंद हो जाता है। हृदय की धड़कन बंद होने की स्थिति में मृत्यु स्वाभाविक है। लेकिन पायलट बाबा का शरीर जीवित रहता है। जनवरी, १९८८ के तृतीय सप्ताह में १९ से २१ तारीख तक भारत निर्माण संस्था के तत्वावधान में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय आध्यात्मिक पुनर्जागरण सम्मेलन में पायलट बाबा ने समाधि लगायी। पायलट बाबा का नाम था—कपिल। वे भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर रह चुके हैं। १९८३ में उन्हें वीरचक्र से सम्मानित किया गया था।

एक बार नेफा क्षेत्र में तीन अन्य विमानों के साथ कपिल उड़ान पर थे। अचानक उनके विमान बवंडर में फंस गये। उनके दोनों साथी विमान भी दुर्घटनाग्रस्त होने वाले थे। अकस्मात एक महात्मा ने उड़ते हुए कपिल के विमान में प्रवेश किया और काकपिट में बैठकर विमान को चलाने लगे। कपिल के साथ दो अन्य पायलट भी इस चमत्कार को देख रहे थे। महात्मा ने विमान को हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया और अदृश्य हो गये। जांच से पता चला कि विमान पूर्णतः बेकार हो चुका था। यह वही साधु था जिसे कपिल अपने छात्र जीवन में २ रुपए की भिक्षा दिया करते थे।

इन घटनाओं से प्रेरित होकर कपिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उस साधु की खोज में जुट गये जो उनके छात्र जीवन से ही अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा उनकी रक्षा कर रहा था। अन्ततः कपिल ने नेपाल में नारायणी नदी के किनारे उस साधु को खोज निकाला। उस महान योगी हरिबाबा ने कपिल को योग की दीक्षा दी। अपने गुरु के आदेशानुसार कपिल योग साधना में रत रहने के लिए हिमालय के १५००० फुट ऊंचे ग्लेशियर पर चले गये।

पायलट बाबा एक ऐसी योजना बना रहे हैं, जिसके अंदर पूर्ण शून्य (एब्सोल्यूट वैक्यूम) की रचना की जायेगी। वहां परमाणु बम का विस्फोट नहीं हो सकेगा। योग-बल के द्वारा ऐसी स्थिति लायी जा सकेगी या नहीं, कहना कठिन है।

महामानव स्वामी मृत्युंजय: स्वामी प्रेमानंदजी मृत्युंजय भारत के उन गिने-चुने विद्वान और तपस्वी संतों में से एक हैं, जो दुनिया के किसी भी विषय पर तर्क और तथ्यों के साथ धाराप्रवाह बात कर सकते हैं। उनकी जितनी रुचि अध्यात्म में है, उतनी ही रुचि निरस्त्रीकरण में भी है। कई भाषाओं के ज्ञाता स्वामी मृत्युंजय से भारत के किसी भी वेद-पुराण अथवा धर्म ग्रंथ का कोई भी श्लोक या प्रकरण पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने में देरी हो सकती है, पर उत्तर में नहीं। शायद इसी कारण साधु समाज में उनके दिमाग को कम्प्यूटर की उपमा दी जाती है। मप्र के एक राजघराने में जन्मे स्वामी मृत्युंजय साधु समाज में ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों में भी बेहद लोकप्रिय हैं।

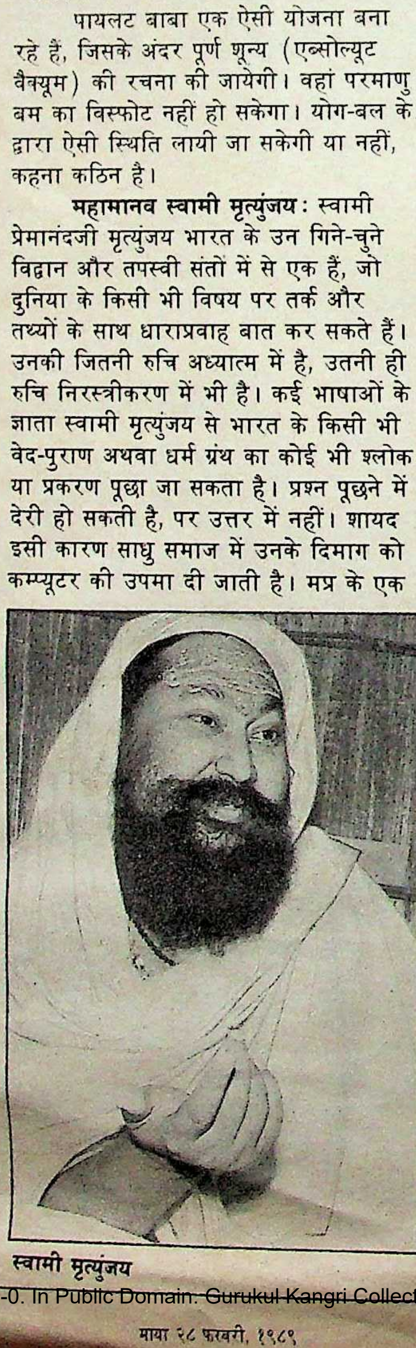

स्वामी मृत्युंजय

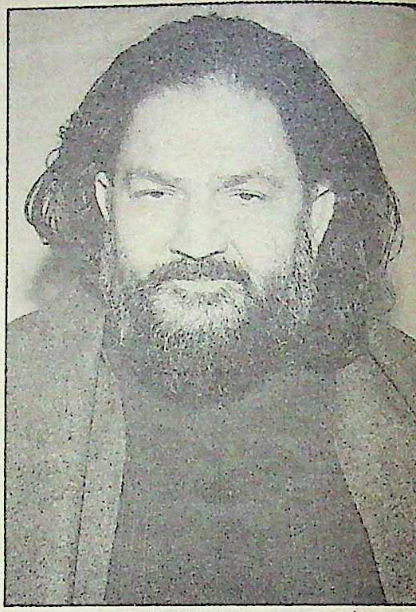

सूफी कलन्दर तबरेजी

स्वामी श्री मृत्युंजयजी महाराज कामरूप कामाख्या और हिमालय पर्वत के कितने ही गुप्त स्थानों पर साधना कर चुके हैं। अपने संन्यास का अधिकांश भाग उन्होंने तप-साधना और एकांतवास में गुजारा है। वे कई आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत हैं। पर वे सस्ते चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते। झूठे आडम्बर से उन्हें सख्त घृणा है। स्वामी मृत्युंजय कहते हैं, "सादा जीवन जियो, आडम्बर अंधविश्वास से दूर रहो, सत्कर्म करते रहो। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है!" स्वामी मृत्युंजय जी ने कुंभनगर में भी 'शाम्भव योग पीठम्' शिविर लगाया है।

एक सूफी भी: साधु-संन्यासियों, सूफी-संतों के लिए धर्म की दीवारें बेहद बौनी होती हैं। सब धर्मों को एक मानना और सब धर्मावलम्बियों को एक-सा उपदेश देना अच्छे संतों की नियति है। सूफी संत आश्रम गिरिडीह से आये सूफी कलन्दर तबरेजी के लिए यह पहला कुंभ नहीं है। वे हर कुंभ में आते हैं। सूफीजी कहते हैं, "बहुत फल हैं, सभी में खुशबू नहीं।" उनका कहने का अभिप्राय यह है कि साधु बहुत हैं, पर मन और आत्मा से कोई-कोई ही संत होता है। सूफी कलन्दर तबरेजी बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं। भारत के महान और पहुंचे हुए हिंदू संतों से उनके अच्छे संबंध हैं। सर्वधर्म सम्मेलनों में भी उनकी बराबर शिरकत रहती है।

—पुष्कर पुष्प

महिला अवधूतों का जुलूस

किसिम-किसिम के अखाड़े

कुंभ-अर्धकुंभ के मुख्य स्नान पर्वों पर शाही जुलूस की शक्ल में परंपरागत हथियार, वेशभूषा का प्रदर्शन करते निकलने वाले अखाड़ों का अपना एक फौजी इतिहास है। जब मुगल काल में राष्ट्र और धर्म अपमानित किया जाने लगा, तो संन्यासियों ने संगठित होकर अपने को नागा सैनिक और अपने संगठन को अखाड़ों का नाम दिया।

वैसे तो माना जाता है कि मठों का उद्भव किसी-न-किसी रूप में छठी शताब्दी के पूर्व हो चुका था, किंतु मठों का वर्तमान स्वरूप आदि शंकराचार्य ने आठवीं शताब्दी में किया। शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन धर्म-दर्शन का विरोध करने के लिए ब्रह्मवाद तथा अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया और मठों के माध्यम से वैदिक धर्म को पुनः प्रचारित-प्रसारित एवं पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव की दृष्टि से अनेक मठों की स्थापना की। इसके पीछे उनका मंशा था कि बौद्ध धर्म और जैन दर्शन के पराभव के बाद संपूर्ण भारत में वैदिक धर्म के प्रति आस्था और विश्वास की जो लहर पैदा हुई है, वह समाज में शाश्वत बनी रहे। इसके लिए शंकराचार्य ने देश के चार कोनों में शारदापीठ, गोवर्धनपीठ, ज्योतिषपीठ और शृंगेरीपीठ मठों की स्थापना की और संन्यासियों को दस भागों में बांटकर उनके आवास एवं भौगोलिक परिवेश के अनुसार उनका नामकरण किया। ये दस वर्ग थे--गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर और सरस्वती। 'अखाड़ा' मठों का एक विशिष्ट प्रकार है।

दरअसल, बौद्ध और वैदिक धर्म का टकराव इतिहास के प्रारंभिक काल से ही हो गया था और यह एक शुरुआत थी तथा भविष्य में धार्मिक संकटों अथवा टकराव का संकेत। बिखरे हुए समाज में धर्मानुयायी अथवा इधर-उधर धूनी रमाते योगी, साधु भी ऐसी चुनौतियों का सामना न कर सकेंगे। अतः ऐसे में समाज के साथ साधुओं का भी संगठन आवश्यक हो गया था। इन दोनों दृष्टियों से आदि शंकराचार्य (७८८-८२०) देश में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते रहे और वैदिक धर्म की अलख जगाते रहे तथा बौद्ध धर्म की बाढ़ को रोकने के लिए साधु-संतों को एकत्रित कर पहले मठों और फिर अखाड़ों का गठन किया। अखाड़ों की अपनी विशेषताएं हैं। मठों में जहां विभिन्न प्रकार के संन्यासी होते हैं, वहीं अखाड़ों में केवल नागा संन्यासी ही रहते हैं।

आत्मरक्षा और अत्याचारियों के प्रतिकार के लिए संन्यासियों में अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग का प्रचलन शताब्दियों पूर्व से चला आ रहा है। अखाड़ों में शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करने की परंपरा कब चली, यह कहना कठिन है। विदेशी आक्रमणों ने जब शास्त्रार्थ एवं तर्क की अपेक्षा सैन्य बल के बूते पर हिंदू धर्म पर प्रहार किया और उनके तीर्थस्थलों और मंदिरों को गिराना शुरू किया तथा मात्र शास्त्र लेकर चलनेवाले शस्त्रहीन साधु-संतों को मौत के घाट उतारने का कार्य किया--तब राजे-महाराजे, बड़े-बड़े पराक्रमी योद्धा पराजित होकर असहाय हो गये। ऐसे में धर्म तथा साधुओं की रक्षा का कोई विकल्प नहीं रह गया। संभवतः ऐसी ही परिस्थितियों में शस्त्रधारी द्रोणाचार्य, बाल्मीक और परशुराम परंपरा को स्वीकार करते हुए साधु-समाज का सैन्य व्यवस्था के आधार पर संगठन किया गया।

वैसे परंपरागत ढंग से इन अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य के काल से ही बतायी जाती है, पर इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा माना जाता है कि बनारस के मधुसूदन सरस्वती ने संभवतः सम्राट अकबर की स्वीकृति से बीरबल और रहीम खानखाना की सहायता से अखाड़ों के संगठन को मजबूत आधार दिया।

देखा जाये तो अखाड़ों को सांप्रदायिक आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। यह विभाजन उनके धार्मिक जीवन-दर्शन पर आधारित है। इनमें एक अखाड़ा शैव संप्रदाय के नागा संन्यासियों का है तथा दूसरा वैष्णव वैरागियों का। इन दोनों संगठनों का उदय सन् १६०० तक हो चुका था।

आवाहन अखाड़ा: मिरिंच गिरि तथा दीनानाथ गिरि आदि ने ५४७ ई० में इस अखाड़ा को स्थापित किया। इसके इष्टदेवता गणपति हैं और मुख्य गद्दी दशाश्वमेध, बनारस में है।

अटल अखाड़ा: इस अखाड़े के निर्माण में वनखंडभारती, सागर भारती, शिवनारायण भारती आदि कई नामों की गणना की गयी है। अटल अखाड़ा की स्थापना ६४७ ई० में गोंडवाना में हुई थी। इसके इष्टदेवता गणेश हैं। इसका मुख्यालय चाक हनुमान, कतुआपुरा बनारस में है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस अखाड़े ने अनेक योद्धा संन्यासियों को जन्म दिया है। कुंभ मेले में यह भोजनादि के लिए निर्वाणी अखाड़े में सम्मिलित होते हैं। दरअसल, यह अखाड़ा एक तरह से निर्वाणी अखाड़े से संबद्ध है।

आनंद अखाड़ा: इस अखाड़े की स्थापना केयागिरि महाराज तथा रामेश्वर गिरि आदि ने ८५५ में बरार में किया। इसके इष्ट देवता सूर्य यानी अग्नि देवता हैं। इसका मुख्यालय कपिल धारा, बनारस में है।

निरंजनी अखाड़ा: माण्डवी (कच्छ) में ९०४ ई० में स्थापित निरंजनी अखाड़ा का शुभमुहूर्त अत्रि मौनी सिद्ध सरजूनाथ पुरुषोत्तम गिरि ने कराया था। इस अखाड़े के इष्टदेव कार्तिकेय हैं। इसका मुख्यालय मायापुर, हरिद्वार में है।

निर्वाणी अखाड़ा: ७४९ ई० में कुण्डागढ़ (झारखंड-बिहार) के सिद्धेश्वर मंदिर में स्थापित निर्वाणी अखाड़ा शैवों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस अखाड़ा के नागा संन्यासियों ने औरंगजेब के विरुद्ध १६६४ में बनारस की रक्षा के लिए ज्ञानवापी पर दो युद्धों में भाग लिया था। यह अखाड़ा कपिल महामुनि का उपासक है। इसकी प्रमुख गद्दी दारागंज, प्रयाग में है। यह अखाड़ा अपने सिद्ध महंतों के लिए विख्यात है। इसका झंडा सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश है। वर्तमान में यह सबसे अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली अखाड़ा है।

जूना अखाड़ा: शैव अखाड़ा के छह प्रमुख अखाड़े हैं। ये शैवों के अति प्राचीन संप्रदाय 'कापालिक' का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सबसे पुराना 'जूना अखाड़ा' है। अन्य अखाड़ों से इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें नागा महिलाएं रहती हैं जिन्हें 'अवधूतनी' कहते हैं। इसके निर्माता मोहाम गिरि, सुंदर गिरि, मौनी दिगम्बर आदि थे। जूना अखाड़े को भैरवी अखाड़ा भी कहते हैं। यद्यपि इस अखाड़े की स्थापना १०६० ई० में कर्ण प्रयाग (उत्तर काशी) में हुई थी, किंतु अब इसकी गद्दी बड़ा हनुमान घाट बनारस में है तथा शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यम्बक में हैं। इसके इष्टदेव

भगवान दत्तात्रेय (भैरव) हैं। जूना अखाड़े से संबद्ध अखाड़े हैं—अगन (अग्नि), अलखी, सुखड़ और गूदड़।

अग्नि अखाड़ा: आदि शंकराचार्यों ने चारों पीठों में क्रमशः आनंद, चैतन्य, ब्रह्मचारी नियुक्त कर वेद, पुराण, उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन, मनन, पूजा, उपासना व यज्ञादि कर्मकांड करने का विधान उनके लिए निश्चित किया। कालांतर में अन्य अखाड़ों की स्थापना में चतुर्नाम्ना ब्रह्मचारियों का भी एक अखाड़ा श्रीपंच अग्नि अखाड़ा के नाम से बनारस में वि०सं० ११९२ आषाढ़ शुक्ला एकादशी को स्थापित हुआ। इस अखाड़े का मुख्य केंद्र राजघाट बनारस में है। इसकी इष्ट देवी 'गायत्रीमाता' और इष्टदेव अग्नि हैं। इस अखाड़े की विशेषता यह है कि इसमें नागा संन्यासी नहीं हैं। इसमें केवल चारों पीठों के ब्रह्मचारी ही हैं।

वैष्णव अखाड़ा: वैष्णव अखाड़ा के उद्भव का समय सन १६५० से १७१३ के बीच माना जाता है। पर एक अन्य मान्यता के अनुसार इसकी स्थापना का काल सन १७२६ भी माना गया है। इस अखाड़े की स्थापना शैव अखाड़ों के विरुद्ध हुई थी। इसके संगठन को मजबूत बनाने के लिए रामानंदी संप्रदाय के बालानंदजी ने काफी प्रयास किया था। इसके पहले वैष्णवों का कोई अखाड़ा नहीं था। वैष्णव अखाड़े का प्रमुख स्थान दारागंज, प्रयाग है। बालानंदजी ने सैनिक डिवीजन की तरह तीन 'अनी' का निर्माण किया। ये थे—दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी। दिगंबर अनी के महंत इन दोनों से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। बालानंदजी ने दिगंबर, निर्मोही, खाकी, निरालंबी, संतोषी निर्वाणी और महानिर्वाणी अखाड़ों की स्थापना की थी। 'अनी' का संगठन कुंभ मेला के अवसर पर विशेष रूप से सजधजकर अपनी वेषभूषा में मार्च करता है। दिगंबर अखाड़े का ध्वज पांच रंगों का होता है। उसे 'पंचरंग' ध्वज कहते हैं। अन्य दोनों अनियों में श्वेत रंग का ही ध्वज होता है। रामानंदी संप्रदाय के अखाड़ों में बाहर की ओर ध्वज पर हनुमानजी का और भीतर की ओर सूर्यनारायण का चिह्न बना होता है। किंतु अन्य संप्रदायों के अखाड़ों के ध्वजों पर बाहर तो हनुमानजी का ही चिह्न होता है, पर भीतर गरुड़ का चिह्न बना रहता है।

उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा: अपने देश में उदासीन संतों की भी एक कोटि है। उदासीन महापुरुष उन संतों में आते हैं जो किसी भी दशा में अपने स्वार्थ का विचार नहीं करते। उदासीन शब्द का अर्थ है—आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठा हुआ व्यक्ति। उदासीन संतों की परंपरा उतनी ही प्राचीन है, जितना प्राचीन वेद है या वेदविहित समाज।

उदासीन संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय श्री चंद्राचार्य को है, जिन्होंने चार धूणें और छह बख्शीशों की वरिष्ठ परंपरा चलायी, जिसके अंतर्गत अनेक तपस्वी महापुरुषों ने ज्ञान-विज्ञान का प्रचार करते हुए गृहस्थों और सामान्यतः जन समुदाय को अपनी कृपा से तृप्त, तुष्ट और पुष्ट किया। वर्तमान में उदासीन संप्रदाय के दो अखाड़े हैं—पहला, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा तथा दूसरा, उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। वि०सं० १८४५ में कीडगंज, प्रयाग में उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा स्थापित हुआ।

उदासीन नया पंचायती अखाड़ा: सं० १९०२ में उदासीन नया अखाड़ा का जन्म हुआ। इसके जन्म के पीछे उदासीन संतों का आपसी वैमनस्य रहा। कई महंतों ने मिलकर प्रयागराज बांध के महात्मा सूरदास के नेतृत्व में अलग जमात बांधी और उसका नाम उदासीन नया अखाड़ा रख दिया। तब से पहले वाले अखाड़े का नाम उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा पुकारा जाने लगा। उदासीन नया अखाड़ा का मुख्य स्थान हरिद्वार, प्रयाग (मुट्ठीगंज), गया, काशी और कुरुक्षेत्र है। यह अखाड़ा ६. जून, १९१३ को पंजीकृत हुआ।

निर्मल पंचायती अखाड़ा: अखाड़ों के क्रम में एक अखाड़ा निर्मल पंचायती अखाड़ा भी है। निर्मल संप्रदाय का आविर्भाव गुरु नानकदेव से हुआ है और उसी समय से निर्मल संप्रदाय की अभिवृद्धि हुई है। निर्मल पंचायती अखाड़ा जिस प्रकार से मुस्लिम कालीन संकट के पूर्वार्द्ध में रामानंदी वैष्णव संप्रदाय ने और मध्य काल में-उदासीन साधुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार से इस संकट के अंतिमकाल में निर्मल संप्रदाय ने अपने निर्मल साधुओं का एक अखाड़ा संगठित करने की आवश्यकता महसूस की। १९१२ के हरिद्वार कुंभ में महाराजा पटियाला के सहयोग एवं सहायता से तत्कालीन संतबाबा महताब सिंह की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र की विचार गोष्ठी में निर्मल पंचायती अखाड़े के संगठन की रूपरेखा तैयार की। सं० १९१८ भाद्रसुदी द्वादशी को निर्मल अखाड़ा की स्थापना हुई। बाबा महताब सिंह इसके सर्वप्रथम श्रीमहंत बने।

अखाड़े की जमात में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है, जो किसी मठ, संन्यासी या जमात द्वारा स्वीकार किया गया हो। शारीरिक दक्षता अखाड़े में शामिल होने की एक अनिवार्य शर्त है। संन्यासियों की अनेक परंपराओं में यद्यपि, नागाओं द्वारा परिवर्तन ला दिया गया है, किंतु जाति का प्रभाव अभी भी वहां है। शूद्रों का अखाड़े में प्रवेश बिलकुल वर्जित है। नागा लोग बाल रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। बाल बढ़ाने वाले नागाओं में उसे बांधने की अलग-अलग रीतियां प्रचलित हैं। निर्वाणी अखाड़ा के नागा सिर के दाहिनी ओर बाल बांधते हैं, किंतु निरंजनी अखाड़े के लोग इसे बीचोबीच सिर पर बांधते हैं। नागा संन्यासी अपने भाले और बर्छी की पूजा करते हैं। अखाड़े की सदस्यता पा लेने पर नागा संन्यासी को पहले 'वस्त्रधारी' की संज्ञा दी जाती है। वस्त्रधारी होने के बाद महामंडलेश्वर उन्हें संन्यास मंत्र से दीक्षित करते हैं। इसके बाद 'तंगतोड़' संस्कार होता है। फिर हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले में उन्हें पूर्ण रूप से नागा बना दिया जाता है। महाकुंभ प्रयाग के अवसर पर २०० लोग पूर्ण रूप से नागा हुए।

अखाड़ों की संपत्ति: प्रत्येक अखाड़ों के पास अपनी भूमि, भवन, दुकान आदि स्थायी संपत्ति हैं, जो उन्हें दानस्वरूप प्राप्त हुए हैं। अखाड़ों के आय का एक स्रोत दान भी है जिसमें उन्हें भूमि, भवन, धन आदि मिलते रहते हैं। भवनों, दुकानों से प्राप्त किराया भी इनके आय के स्रोत हैं। कुछ अखाड़ों में ब्याज पर ऋण का लेनदेन भी होता है। यह व्यापार धीरे-धीरे तेजी से पनप रहा है। इससे कई महंतों की चांदी हो रही है।

प्रायः सभी अखाड़ों के पास निजी मंदिर हैं। संपत्तियों की व्यवस्था प्रत्येक अखाड़े पर नियुक्त 'थानापति' (कोतवाल) करता है। 'थानापति' अखाड़े के नागाओं में से 'श्रीपंच' द्वारा चुना जाता है। कुछ अखाड़ों में संपत्ति का अधिकार 'पंच' के पास है, तो कुछ में नागा अपनी वैयक्तिक संपत्ति भी रखते हैं। कुछ अखाड़ों की व्यवस्था तो इतनी अच्छी है कि कोई महंत संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। एक तरह से संपत्ति का स्वत्वाधिकार आठ 'श्रीमहंतों' के पास सम्मिलित रूप से रहता है। ये आठों महंत एक या दो व्यक्तियों को कानूनी मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त कर देते हैं। साथ ही ये आठों महंत एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। परिणाम यह होता है कि अखाड़ों की संपत्ति को न तो कोई बेच सकता है और न ही कोई अन्य उसका दुरुपयोग ही कर सकता है।

उदासीन नया अखाड़ा के महामंडलेश्वर और श्रीमहंत

वैसे तो अखाड़े पंचायती व्यवस्था चलाते हैं। इनका स्वरूप भी प्रजातांत्रिक होता है। अखाड़ों का सर्वोच्च व्यक्ति आचार्य महामंडलेश्वर होता है। इसके बाद मंडलेश्वर होते हैं। लेकिन इनके हाथों में निर्णायक शक्ति नहीं होती। निर्णायक अखाड़े का सेक्रेटरी होता है। १९१३ में अखाड़ों का पंजीकरण शुरू हुआ, तब से सेक्रेटरी का महत्व बढ़ा है। प्रत्येक अखाड़े में एक पंच (पार्लियामेंट) होता है।

इस पंच के सदस्य 'श्रीमहंत' कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयाग में अर्धकुंभ और कुंभ के अवसर पर यानी छह साल के बाद 'साहिबी' बदलती है। साहिबी का मतलब अखाड़ों की सरकार से है। प्रयाग में इसका निर्णय होता है और इसको अंतिम रूप बनारस में दिया जाता है। इस दृष्टि से प्रयाग का अर्धकुंभ—कुंभ साधुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और राजनीतिक गहमागहमी से भरा होता है।

—दिनेश दीनू

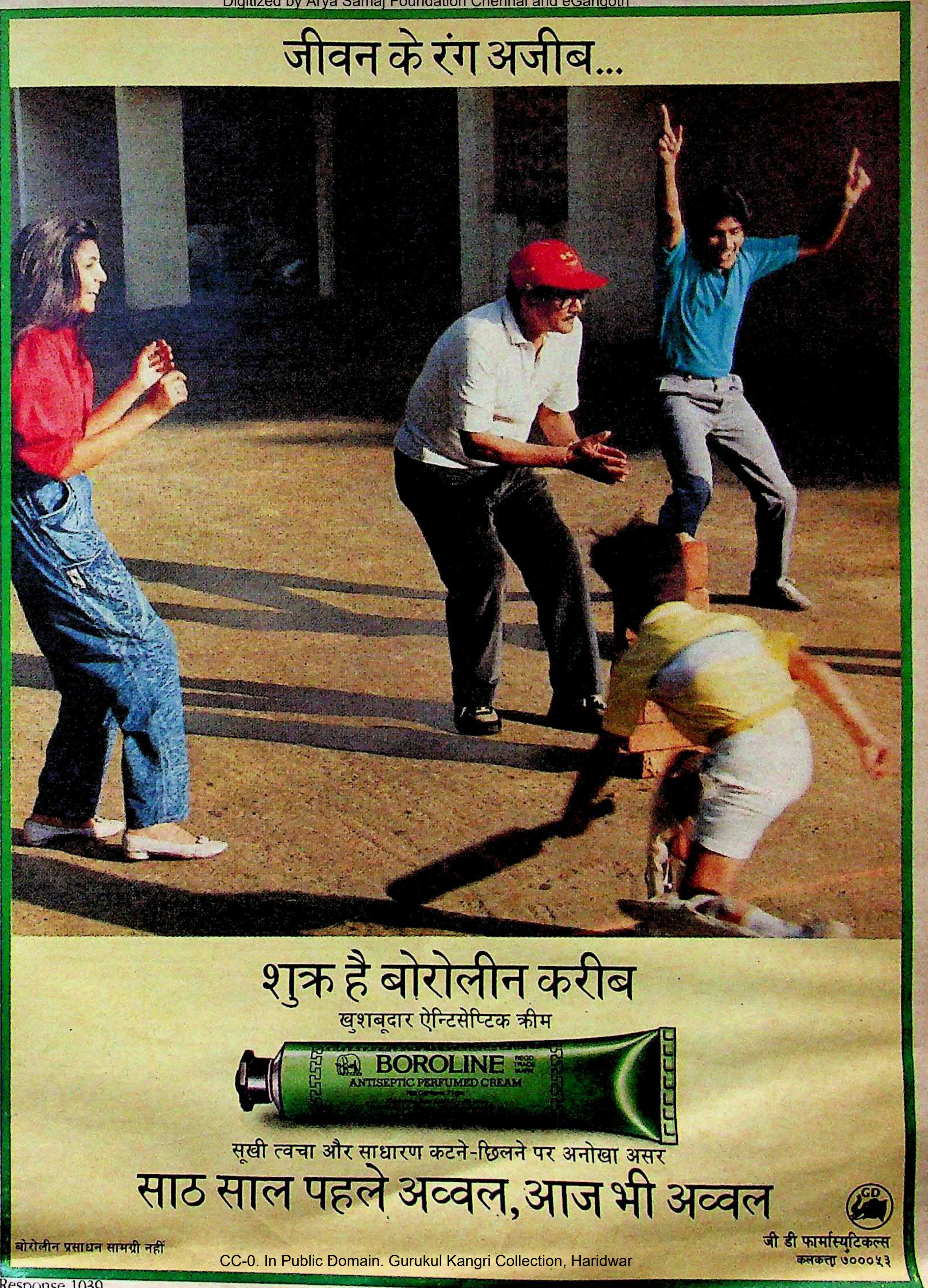

जीवन के रंग अजीब...

शुक्र है बोरोलीन करीब

खुशबूदार ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

BOROLINE
REGD TRADE MARK
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM

सूखी त्वचा और साधारण कटने-छिलने पर अनोखा असर

साठ साल पहले अव्वल, आज भी अव्वल

बोरोलीन प्रसाधन सामग्री नहीं

GD

जी डी फार्मास्युटिकल्स
कलकत्ता ७०००५३

Response 1039

कांग्रेस में खुली बगावत

क्या राजीव संभाल पायेंगे ?

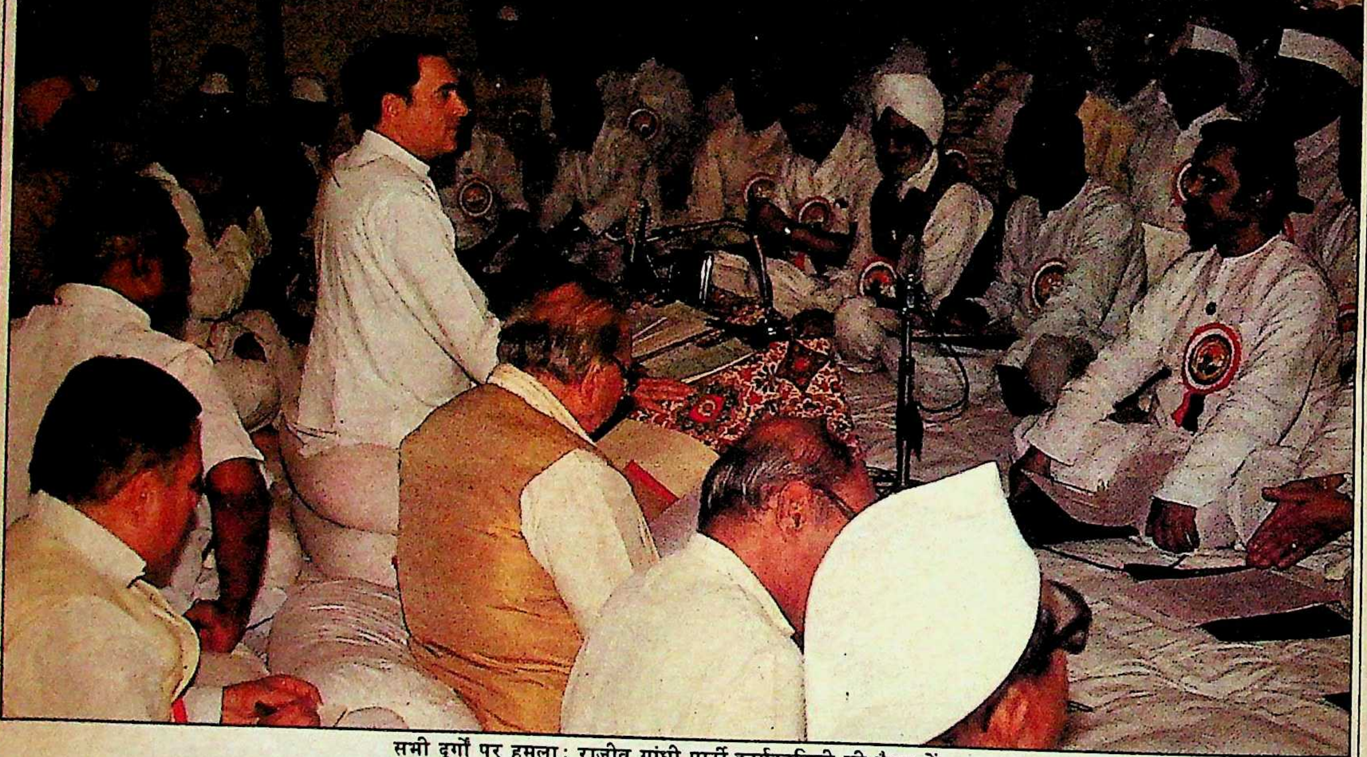

सभी दुर्गों पर हमला : राजीव गांधी पार्टी-कार्यकारिणी की बैठक में

आम चुनाव के पहले
अंतिम विधानसभायी चुनावों में कांग्रेस ने यद्यपि मिजोरम और
नगालैंड में सरकारें बनायी हैं, लेकिन
तमिलनाडु के कांटे के चुनाव में पराजित होने के बाद मध्यप्रदेश, बिहार,
गुजरात और राजस्थान में कांग्रेसियों ने बगावत का बिगुल
बजा दिया है। इस विद्रोह ने अचानक इतना उग्र रूप क्यों
धारण कर लिया और क्या राजीव इसका दमन करने की
स्थिति में हैं ?

यों तो कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों को उखाड़ने का काम काफी समय से चलता रहा है, लेकिन तमिलनाडु में पराजित होने के बाद राज्यों में राजीव गांधी की इच्छाओं और आदेशों की अवहेलना ने जो व्यापक और उग्र रूप धारण किया है, वह अभूतपूर्व है। मिजोरम और नगालैंड में कांग्रेस-इ की सरकारें बनने के बावजूद तमिलनाडु की हार ने कांग्रेसियों का मनोबल घटाया है और उनमें असुरक्षा की भावना तेजी से घर कर गयी है। सबसे खतरनाक बात यह हुई है कि कांग्रेसियों को राजीव गांधी की वोट दिलाने की क्षमता पर भरोसा नहीं रहा। इसका कारण है राजीव गांधी का विधानसभायी चुनाव में अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाना। इसके सबसे ज्वलंत दो उदाहरण हैं: १९८७ में राजीव गांधी ने पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा को पराजित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगाया था, लेकिन वहां मोर्चे को पराजित करना तो दूर, उलटे सीटें ५६ से घट कर ४० हो गयी थीं। उस आघात से राजीव गांधी ने कोई सबक नहीं लिया और इस बार वे तमिलनाडु में सिर के बल चुनाव में लग गये। चुनाव-घोषणा के बाद राजीव गांधी ने तमिलनाडु के १२ दौरे किये। लेकिन नतीजे आये, तो करुणानिधि के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा प्रचंड बहुमत से जीता। ऐसा होना ही था, क्योंकि राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए बेहद भोथरे हथियार इस्तेमाल किये। उनका एक ओर जहां नारा था—तमिलनाडु को द्रविड़वादी पार्टियों से मुक्ति दिलाओ, तो दूसरी ओर नारा था—कामराज का सपना साकार करो। शायद राजीव गांधी और उनके सलाहकार भूल गये कि तमिलनाडु में द्रविड़ भावनाएं प्रबल हैं और स्वयं कांग्रेस ने कामराज को आखिरी दिनों में काफी जलील किया था। लेकिन तमिलनाडु के मतदाता भूले नहीं थे। नतीजतन उन्होंने कांग्रेस को चित कर दिया और जयललिता, जानकी रामचंद्रन, वैजयंतीमाला और बाप का चुनाव-प्रचार करनेवाली श्रीदेवी के फिल्मी लावण्य से बिना मोहित हुए स्थायी सरकार के लिए करुणानिधि को जम कर मत दिया।

चुनाव से पहले ही यह हवा बन चुकी थी कि तमिलनाडु का चुनाव तय करेगा कि राजीव गांधी कितने पानी में हैं। इसलिए जब चुनाव-नतीजे सामने आये, तो विपक्ष मुखर होकर और कांग्रेसियों ने अपने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुहिम तेज करके यह जताना शुरू कर दिया कि राजीव गांधी का न जनता पर और न पार्टी पर कोई प्रभाव है।

मध्य प्रदेश : सबसे पहला विस्फोट हुआ मध्य प्रदेश में। यद्यपि अर्जुन सिंह का पद चुरहट लाटरी पर अदालती फैसले के कारण छिना, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के चयन में जो भयावह खींचातानी (देखिए संलग्न कथा) हुई, उसने यह जाहिर कर दिया कि पार्टी दो स्पष्ट खेमों में बंट गयी है—एक खेमा अर्जुन सिंह का और दूसरा माधवराव सिंधिया का। मध्य प्रदेश अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए सर्वाधिक सुरक्षित राज्य था और उत्तराधिकारी के चयन में दो खेमों के बीच यह कड़ुवाहट नहीं होती, तो चाहे सिंधिया और अर्जुन सिंह में कितनी भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती, लेकिन अंततः दोनों का जोर 'बजाय एक दूसरे के लोगों को हराने के, अपने-अपने लोगों को जिताने में लगता और इसका अंतिम लाभ कांग्रेस को होता। लेकिन अब ऐसे आसार नजर नहीं आते। अर्जुन सिंह के नुमाइंदे दिग्विजय सिंह को बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री न बनने देने के पीछे अर्थ यह लगाया जा रहा है कि हाईकमान अर्जुनसिंह का मध्यप्रदेश में वर्चस्व नहीं चाहता। यदि हाईकमान का रुख अर्जुन सिंह के जनाधार और प्रभाव को नेस्तनाबूद करने का आगे भी चलता रहा, तो सन्निकट आमचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना मुश्किल है। यद्यपि माधव राव सिंधिया को एक ईमानदार और कुशल

वफादार सिपाही, पर संदेहास्पद : अर्जुन सिंह

छाया : रवि

यदि हाई कमान का रुख अर्जुन सिंह के जनाधार और प्रभाव को नेस्तनाबूद करने का आगे भी चलता रहा, तो सन्निकट आम चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, कहना मुश्किल है

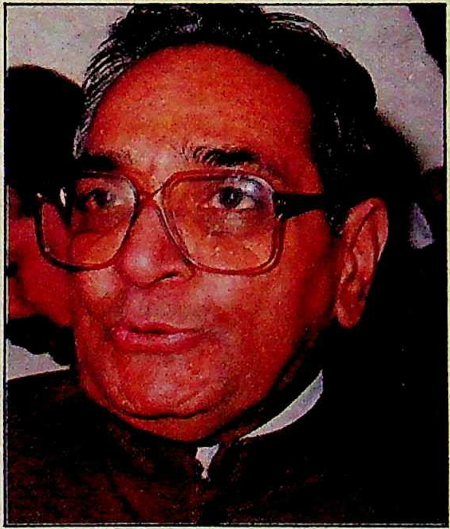

अर्जुन सिंह से टक्कर : मोतीलाल वोरा छाया : आरसी साह

बिहार राजनीति के एक दिग्गज कांग्रेसी खिलाड़ी ने 'माया' से कहा, "बिहार ही तय करेगा कि राजीव गांधी दिल्ली के बहादुर शाह जफर बनेंगे या नहीं।"

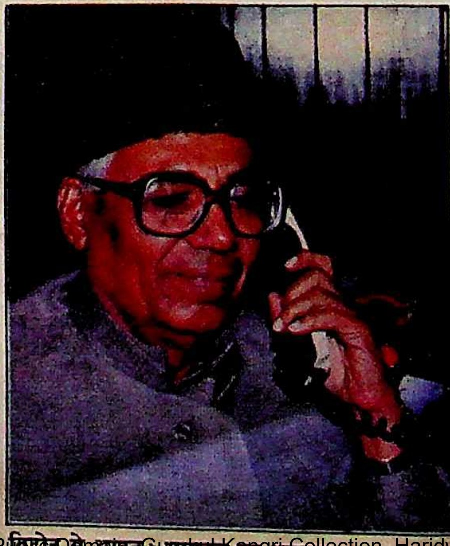

बिहार के आहत : भागवत झा आजाद छाया : दीपक कुमार

रेल मंत्री के रूप में धाक है। राजघराने से संबद्ध और नौजवान होने तथा प्राइवेट ट्रक लाबी के प्रलोभनों को ठुकराकर इंदौर से दिल्ली तक सीधी रेल-सेवा मुहैया करवाने के कारण भी वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक शक्ति हैं, लेकिन यदि इस शक्ति का उपयोग अर्जुन सिंह की ताकत को बेअसर करने के लिए हुआ, तो इसके परिणाम कांग्रेस के लिए घातक होंगे। उत्तराधिकारी के चयन में अर्जुन सिंह-समर्थकों ने जो विद्रोही रवैया अपनाया, उससे साफ जाहिर है कि उनके सब्र का प्याला भर चुका है। उन्हें राजीव गांधी के बजाय अर्जुन सिंह में चुनाव जिताने की ताकत ज्यादा नजर आती है।

बिहार : बहरहाल, मध्य प्रदेश में तो विद्रोह उतना उग्र नहीं हुआ, लेकिन बिहार में यह सारी सीमाएं तोड़ चुका है। आलाकमान द्वारा भेजे गये प्रेक्षकों की लाख कोशिशों (देखिए संलग्न कथा) और पटना-दिल्ली के बीच दौड़ लगाने के बावजूद विद्रोही इस बात पर अड़े रहे कि आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन की बात पहले माने। अंततः समझौता इसी बात पर हुआ कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन इसका फैसला राजीव गांधी करेंगे।

आस्कर की बोलती बंद

जगन्नाथ मिश्र,
पूर्व मुख्यमंत्री बिहार

कोई भी आंदोलन एमएलए की अपनी नाराजगी का द्योतक नहीं, जनाधारित होता है। यदि किसी नेता को जनता का समर्थन हो, तो उसका इतना विरोध कभी नहीं किया जा सकता है। अधिकांश विधानसभा सदस्य वही कदम उठाते हैं जो उनका हित साधने वाला हो। चूंकि आज हर सदस्य को मालूम है कि जनता का रुख मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के खिलाफ है, तो उनकी खिलाफत कर वह अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है।

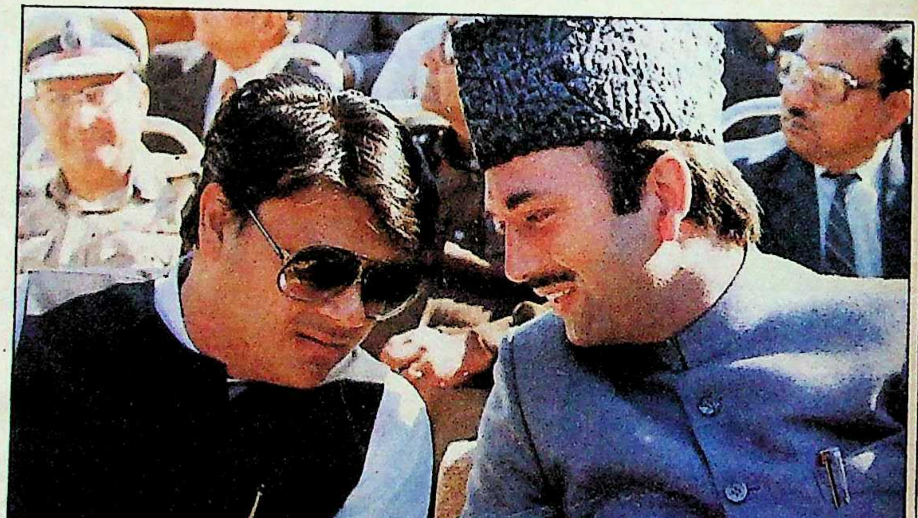

अर्जुन सिंह की चुनौती से चिंतित : गुलाम नबी आजाद और माधवराव सिंधिया

राजीव गांधी ने अभी तक जगन्नाथ मिश्र को नहीं पूछा था, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा और संकट टालने के लिए जगन्नाथ मिश्र की सहायता की गुहार करनी पड़ी।

गुजरात : बिहार जैसी ही स्थिति गुजरात में है। अमर सिंह चौधरी के खिलाफ जिनाभाई दारजी ने मोर्चा खोल दिया है। चार फरवरी को सूरत क्षेत्र में दोनों धड़ों की निर्णायक मुठभेड़ तो आलाकमान के बीच-बचाव से टल गयी है, लेकिन यह युद्ध विराम है, युद्ध-शांति नहीं है। चार फरवरी को दोनों धड़ों ने समानांतर सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया था। इस सम्मेलन का तात्कालिक कारण था ऊकाई सहकारी चीनी मिल की प्रबंध समिति को भंग करना। इस समिति के स्वामी थे, सांसद जीतूभाई गामित जो केंद्रीय योजना मंत्री माधव सिंह सोलंकी और जिनाभाई दारजी के कृपापात्र हैं। इस सम्मेलन के विरोध में सम्मेलन आयोजित करने की ठानी थी सूरत जिला पंचायत के अध्यक्ष सहदेव चौधरी ने। सहदेव चौधरी इस समय पार्टी से निष्कासित हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी के चहेते हैं।

गुजरात में विद्रोह का आलम यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विक्षुब्ध विधायकों ने धमा-चौकड़ी मचा दी थी। इसके अतिरिक्त पार्टी विधायकों की बैठक में भी अमर सिंह चौधरी के समर्थकों और विरोधियों के बीच

केदारनाथ सिंह,
कांग्रेस महासचिव

जहां हमारी पार्टी और शासन बीसों वर्षों से था ही नहीं, उसकी हार पर कोई रोना नहीं।

पर्यवेक्षक या मूक दर्शक ? : पर्यवेक्षकों के बीच अर्जुन सिंह

अर्जुन शिविर में गृह मंत्री भारत सिंह, आवास मंत्री विष्णु राजोरिया, उप मंत्री रामेश्वर पटेल और कपड़ा निगम के चेयरमैन हरवंश सिंह ने मोर्चे संभाल लिये थे। रातोरात समर्थक विधायकों को राजधानी में पहुंचने के लिए संदेश भेजे गये। और तो और, कई विधायकों को वायरलैस के माध्यम से जिलाधीशों के जरिये संदेश देकर भोपाल बुलाया गया। हरवंश सिंह, भारत सिंह, राजोरिया, पटेल और जगतपाल सिंह के बंगलों पर अर्जुन समर्थकों की बैठकों का दौर दो तीन दिनों तक चलता रहा। क्षोभ व हताशा के माहौल में अपने नेता के लिए जीने-मरने की कसमें खायी गयीं और अंततोगत्वा यह सामूहिक मनःस्थिति बनी कि संघर्ष किया जाये।

ऊहापोह की यह तनावभरी स्थिति २२ जनवरी की शाम तक रही, जब दिल्ली में इंका कार्यसमिति की बैठक में अर्जुन सिंह अपनी पहली लड़ाई हार गये और यह तय हुआ कि सिंह को भोपाल जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देना चाहिए। हालांकि दिल्ली में अर्जुन समर्थक लाबी की दलील थी कि कानूनी दृष्टि से हाईकोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है और सिंह के त्यागपत्र से प्रदेश में इंका की स्थिति कमजोर होगी और इसका लाभ सीधे-सीधे भाजपा को मिलेगा। लोगों का कहना है कि शिवशंकर जहां त्यागपत्र के विरोधी थे, वहीं श्रीमती शीला दीक्षित इस्तीफा दिलाने के पक्ष में थीं। जानकार सूत्रों के अनुसार इस संबंध में नेपथ्य में एचकेएल भगत, नटवर सिंह और सीताराम केसरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

गुत्थी : २३ जनवरी की सुबह तक मप्र में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर गुत्थी बेतरह उलझ चुकी थी। अर्जुन सिंह के इस्तीफे के निर्देश की खबर जब उनके समर्थकों को मिली, तो उनमें क्षोभ फैल गया। उनके प्रवक्ता के तौर पर गुढ़ (रीवा) के विधायक नागेंद्र सिंह ने 'माया' से कहा, "यह मप्र के गरीबों, निर्धनों व सर्वहारा वर्ग के प्रति अन्याय है, जिनके हितार्थ अर्जुन सिंह ने सतत काम किया है। अर्जुन सिंह का इस्तीफा पूंजीवादी, जातिवादी और सत्तालोलुप शक्तियों की जीत है।" हवाई-अड्डे पर अपने नेता की प्रतीक्षा में आतुर नागेंद्र सिंह ने भावुक स्वरों में कहा—"अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री की कुरसी से हटाया जा सकता है, लेकिन उन्हें लाखों लोगों के दिलों से हटाना मुमकिन नहीं है।" नागेंद्र सिंह के इस कथन से अर्जुन-समर्थकों की मनःस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बीच अर्जुन सिंह के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी था और कई विधायकों से हवाई-अड्डे पर ही एक कोने में ले जाकर हस्ताक्षर कराये गये। करीब १० लोगों ने विधानसभाध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इतने विधायकों के हस्ताक्षरों से अब तक यह आभास हो चला था कि उलझी गुत्थी को सुलझाना पर्यवेक्षकों के लिए आसान नहीं होगा। मगर यह अहसास किसी को नहीं था कि समाधान में आलाकमान को खासी दिक्कत उठानी पड़ेगी और उसे पसीना आ जायेगा। (देखे बाक्स)

द्वंद्व : राजधानी भोपाल में अब तक यह भनक लग गयी थी कि अर्जुन सिंह के त्यागपत्र के बाद नये नेता के चुनाव में यह गुट पूर्व प्रदेश इंकाध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह पर दांव लगायेगा। इसकी पुष्टि २३ जनवरी को दोपहर तब हो गयी, जब दिल्ली से पर्यवेक्षक द्वय—गुलाम नबी आजाद और दरबारा सिंह—के साथ अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह और महेश जोशी भोपाल आये। आजाद ने आते ही यह स्पष्ट कर दिया कि विधायकों के बहुमत का आदर किया जायेगा और विधायकों को अर्जुन सिंह के अतिरिक्त किसी का चुनाव करना होगा। अब तक अर्जुन गुट ने अपनी बिखरी ताकत संजो ली थी और उन्हें जीत का पूरा भरोसा था। सांसद द्वय अजीत जोगी और सुभाष यादव तड़के भोपाल आकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में गोटियां बिछाने के खेल में जुट गये थे। पर्यवेक्षकों ने जब विधायकों की अलग-अलग राय जानने की बात कही, तो अरुण तिवारी और देवेंद्र सिंह रघुवंशी सदृश कट्टर अर्जुन-समर्थकों ने अत्यंत आवेश में इसका यह कहकर प्रतिकार किया कि हम लोग कोई नौकरी मांगने नहीं आये हैं कि अलग-अलग इंटरव्यू दें। विधायकों से सामूहिक चर्चा होनी चाहिए। इस समय तक अजीत जोगी, सुभाष यादव, जगतपाल आदि आश्वस्त थे कि दिग्विजय सिंह नये मुख्यमंत्री होंगे। यह खबर दावानल की तरह फैली। परिणामतः एक ओर जहां मिठाइयां बंट गयीं, वहां दूसरा पक्ष हताशा में डूब गया। विरोधी गुट कुछ घंटे बाद इस मनःस्थिति से तब उबरा, जब शाम ढलते-ढलते माधवराव सिंधिया एवं मोतीलाल वोरा करीब एक दर्जन समर्थक सांसदों के साथ चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंच गये। उनके आगमन ने अर्जुन-विरोधी शिविर में नये प्राण फूंक दिये। अर्जुन-विरोधियों को एकजुट करने के काम में अग्रणी रहे कैप्टन जयपाल सिंह तथा बालेंदु शुक्ल के आवास पर बैठकों का दौर शुरू हो गया। तब तक तीसरे पर्यवेक्षक संचार मंत्री वीर बहादुर भी भोपाल आ चुके थे और तीनों शामला हिल स्थित मुख्यमंत्री आवास में विधायकों की राय जानने में मशगूल थे।

सभी का अनुमान था कि देर रात गये तक फैसला हो जायेगा, किंतु सुबह पौ फटने तक फैसला नहीं हो सका। विधायकों, सांसदों एवं पत्रकारों ने तनाव, दुविधा व उत्सुकता के साथ रतजगा करके रात बितायी। अर्जुन गुट बहुमत की राय मनवाने पर अड़ा हुआ था और उन पर मनुहार और दबावों तथा आलाकमान की इच्छा का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा था। प्रदेश इंकाध्यक्ष सांसद चंदूलाल चंद्राकर पार्टी दफ्तर में एकाकी बैठे थे। संपर्क साधने पर अपनी दुश्चिंताओं को छिपाते हुए उन्होंने कहा, "मैं गारंटी देता हूं कि चुनाव परंपरानुसार सर्वसम्मत होगा।" विलंब से संबंधित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, "सवाल मुखिया चुनने का है। कभी यह चुनाव तलवार-बंदूकों से होता था। अब सबकी राय जानकर समझा-बुझाकर रजामंदी से होता है। विलंब में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।" पार्टी दफ्तर के बाहर सांसद महेंद्र सिंह ने 'माया' से कहा, "मप्र में परिस्थितियों और आगामी चुनाव को मद्देनजर रख हमें यहां 'क्लीन और कैरिश्मेटिक लीडर' चाहिए। इसी क्रम में आदिवासी सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने कहा, "अर्जुन सिंह को आलाकमान का फैसला निर्विरोध शिरोधार्य करना चाहिए था। व्यक्तिवादी लीक के बजाय उन्हें पार्टी की सर्वोच्च शक्तिपीठ वर्किंग कमेटी के निर्णय का सम्मान कर मर्यादित आचरण का उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसका अनादर कर उलटे 'क्राइसिस' पैदा की।" अखिल भारतीय कांग्रेस—इ कमेटी के संयुक्त मंत्री भूरिया ने तनिक तल्खी से कहा, "अर्जुन सिंह ने

युद्ध विराम की कोशिश: फोतेदार, अर्जुन और वोरा

अपने आचरण से अपने पावों पर कुल्हाड़ी मार ली है।"

अंतिम चक्र: २४ जनवरी को साढ़े दस बजे प्रदेश कांग्रेस—इ कमेटी में इंका विधायकों की बैठक बुलायी गयी थी, किंतु पार्टी अनुशासन को सामूहिक ठेंगा दिखाते हुए अर्जुन गुट का एक भी व्यक्ति वहां नहीं फटका। हालांकि, युवक कांग्रेस—इ और राष्ट्रीय छात्र संघ के कार्यकर्ता वहां पहुंच गये थे और राजीव गांधी, सिंधिया और वोरा की जय जयकार में लगे हुए थे। अर्जुन-गुट के विधायकों ने मप्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह के चार इमली स्थित बंगले पर डेरा जमा रखा था। बीआर यादव, चंद्र मोहन, गंगा पोटाई, मंजू राय, चरणदास महंत, महेंद्र बहादुर सिंह, महेश जोशी, वंशी लाल धृतलहरे, दाऊ हनुमंत सिंह, भारत सिंह, कमला देवी, चंद्रप्रभाष शेखर, विष्णु राजोरिया, रामजी महाजन, हसनात सिद्दीकी, राजमणि पटेल और रामेश्वर पटेल आदि मंत्री तथा शताधिक विधायक लान में तथा भीतर बंगले में डटे हुए थे। एक तरह से वहां मेले का दृश्य था। नेताओं को बाहर आने तथा पत्रकारों को भीतर जाने की मनाही थी। वक्त गुजारने के लिए हालांकि खानेपीने, शेरो-शायरी और पवन दीवान की कविताओं का दौर चल रहा था, किंतु वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर क्षोभ, तनाव और आक्रोश को अनायास ही पढ़ा जा सकता था। समूचा गुट दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ा हुआ था और यह सामान्य राय थी कि आलाकमान को अपनी इच्छा थोपने के बजाय बहुमत का आदर करना चाहिए। सिंह के कतिपय

साक्षात्कार/अर्जुन सिंह

विद्रोह का सवाल ही नहीं उठता

"राजीवजी एवं पार्टी नेता के प्रति निष्ठा की देहरी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता", पदत्याग और वोरा के नेता चुने जाने के दो दिन बाद शामला पहाड़ी के अपने पूर्वापेक्षा सूने सरकारी बंगले में 'माया' से बातचीत में अर्जुनसिंह ने कहा। सर्वाधिक काल तक मप्र का मुख्यमंत्री रहने का श्रेय प्राप्त अर्जुनसिंह की मेधा, काबिलीयत और संघर्ष-क्षमता गर्दिश के दौर में नये सिरे से कसौटी पर है। प्रस्तुत हैं, उनसे बातचीत के प्रमुख अंश:

माया: *चुरहट लाटरी कांड पर अदालती फैसले के बारे में आपने अंतिम रूप से क्या तय किया है?*

अर्जुन: *यह तो वकीलों की राय पर निर्भर करेगा कि क्या किया जाये, किंतु फिलहाल यह जरूर कहूंगा कि यह फैसला विधिसम्मत नहीं है। मुझे सफाई का मौका दिये बगैर ही केरवां स्थित मेरे आवास गृह के बारे में फैसला दे दिया गया, जबकि यह मुद्दा उच्चन्यायालय द्वारा सूचीबद्ध किये गये मुद्दों में था ही नहीं। जहां तक निर्माण पर व्यय के स्रोतों की बात है, संपत्ति की जांच-पड़ताल के मामले में आयकर विभाग का निर्णय अंतिम व मान्य होता है। जब यह सर्वत्र मान्य है, तो मेरे बारे में पृथक व भिन्न मानदंड क्यों?*

माया: *प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार नये नेता के चुनाव में अनपेक्षित विलंब इस कारण हुआ, क्योंकि आपके समर्थकों ने अड़ियल और उग्र रवैया अपनाया था?*

अर्जुन: *मैंने या मेरे समर्थकों ने न तो अड़ियल रवैया अपनाया और न ही उग्र। पार्टी में सदैव से किसी भी प्रश्न को निबटाने हेतु व्यापक परामर्श होता आया है। यह बात जरूर है कि इस बार व्यापक परामर्श की यह अवधि थोड़ी बढ़ गयी।*

माया: *उड़ीसा के मुख्यमंत्री जेबी पटनायक पर तो आपसे भी गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद उनको इस्तीफा देने के लिए अभी तक बाध्य नहीं किया गया, जबकि उच्चतम न्यायालय के अग्रिम निर्णय का इंतजार किये बिना ही आपको पद त्याग करने के लिए विवश किया गया। क्या आलाकमान ने आपके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया?*

अर्जुन: *मप्र की तुलना उड़ीसा से करना उपयुक्त नहीं। यदि तुलना करनी ही है, तो मैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से करूंगा, जहां मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अदालती फैसले के बावजूद किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। मैंने अपना पद त्याग कांग्रेस की परंपरा को ध्यान में रखते हुए किया।*

माया: *क्या गृहमंत्री बूटा सिंह ने आपको पार्टी से निष्कासन की धमकी दी थी?*

अर्जुन: *यह अफवाह है।*

माया: *आप बरसों बाद पदविहीन स्थिति में हैं। आपने अपने लिए क्या तय किया है?*

अर्जुन: *मैं अपना अधिकांश समय अब पढ़ने-लिखने और पार्टी के कामों में लगाऊंगा। यह जान लीजिए कि मैं समकालीन परिदृश्य से ओझल होनेवाला नहीं हूं।*

माया: *क्या यह सही है कि आपने प्रदेशव्यापी दौरा करने का निश्चय किया है?*

अर्जुन: *जी हां! मैं दौरा करूंगा, लेकिन तारीखें अभी तय नहीं की हैं।*

माया: *क्या यह सही है कि आपके गुट की बैठक में कुछ विधायकों ने विद्रोह की बातें की थीं और यह बार-बार कहा गया कि नेता ऊपर से थोपना नहीं चाहिए?*

अर्जुन: *मैं समझता हूं कि भांति-भांति की जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, वे शनैः-शनैः साफ हो जायेंगी। रही बात विद्रोह की, सो विद्रोह का सवाल ही नहीं उठता। पार्टी और नेता तथा मेरे बीच कोई दरार पैदा करने में किसी ने न तो अभी तक कोई सफलता पायी है और न ही आगे पा सकेगा।*

माया: *क्या आपके समर्थकों की यह राय नहीं थी कि वे माधवराव सिंधिया को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे?*

अर्जुन: *इस तरह की बातों का प्रश्न नहीं उठता। हां, लोगों ने अपनी राय जरूर खुलकर व्यक्त की।*

माया: *भविष्य में आप प्रदेश की राजनीति में रहना पसंद करेंगे या केंद्र में जाना चाहेंगे?*

अर्जुन: *मेरे जाने या चाहने की बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि मैं अपने नेता का आदेश सदैव बेहिचक मानता रहा हूं और आगे भी मानूंगा।*

माया: *नये मुख्यमंत्री वोरा के साथ सहयोग को लेकर आप की क्या नीति रहेगी?*

अर्जुन: *जहां भी वह सहयोग मांगेंगे, मैं दूंगा और जहां नहीं भी मांगेंगे, लेकिन पार्टी का हित होगा, मैं उन्हें बिन मांगे सहयोग दूंगा।*

माया: *मोतीलाल वोरा ने कहा है कि वे पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों और नीतियों की समीक्षा कर उनके बारे में फैसला करेंगे कि क्या किया जाये?*

अर्जुन: *यह (समीक्षा) मुख्यमंत्री के नाते उनका अधिकार है। लेकिन नेता के चुनाव की बैठक में उन्होंने मंच से कहा था कि वे आदिवासियों, हरिजनों व पिछड़े वर्ग के कल्याण की नीतियों व कार्यक्रमों को जारी रखेंगे।*

—सु०स०

कट्टर समर्थक अंजाम की परवाह किये बिना किसी भी हद तक संघर्ष करने के हिमायती थे। इन विधायकों को इसकी रत्तीभर चिंता नहीं थी कि उग्र और अड़ियल रवैये से उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है या पार्टी दो फाड़ हो सकती है। बहरहाल शिविर की आम राय थी कि माधवराय सिंधिया बतौर मुख्यमंत्री इस गुट को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होंगे। सिंधिया के विरोध व दिग्विजय को मुख्यमंत्री बनाने का हठ इतना तीव्र व तीखा था कि लोगों को सहज ही इसमें आलाकमान की अवज्ञा व विद्रोह की बू आने लगी और यह बात पर्यवेक्षकों तक भिन्न-भिन्न सूत्रों व स्रोतों से पहुंची भी।

"एक व्यक्ति ने विद्रोह की बात नहीं की," ठाकुर हरवंश सिंह ने 'माया' से कहा, "सबने पार्टी व राजीवजी में निष्ठा-आस्था व्यक्त की। हम लोगों शुरू में ही आलाकमान की बात मान लेते, अगर हमसे यह नहीं कहा जाता कि आलाकमान विधायकों के बहुमत की इच्छा का आदर करेगा।" जाहिर है कि अपदस्थ होने के बाद पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के शिष्य अर्जुन सिंह ने अपने कूट-कौशल और अपनी ताक़त का इजहार बहुत करीने से कर दिया था। नतीजतन दिल्ली से स्पष्ट संकेत लाने के बाद भी पर्यवेक्षकों की त्रयी पशोपेश में पड़ गयी थी। पुराने राजनीतिक पंडितों के मन में सातवें दशक में पं० डीपी मिश्र, काटजू, देशलहरा और फिर मिश्र व गोविंद नारायण सिंह के बीच चले सत्ता के द्वंद्व की याद ताजा हो आयी थी, मगर इस पर वे भी एकमत थे कि यह दौर अधिक तनावपूर्ण, कठिन, पेचीदा और लंबा है। मामले की पेचीदगी तब एक बार फिर उजागर हुई, जब २४ जनवरी को दोपहर में खबर आयी कि गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वय माखनलाल फोतेदार और बूटा सिंह भोपाल आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दो अत्यंत विश्वासपात्र और निकटस्थ लोगों के आगमन के बाद नेता के चुनाव का मामला अंतिम चक्र—फाइनल राउंड—में पहुंच गया। बूटासिंह और फोतेदार ने आते ही पर्यवेक्षकों से हालात का जायजा लिया। कायदे से विधायकों अथवा उनके चुनिंदा नेताओं को बूटा और फोतेदार के पास जाना चाहिए था, किंतु गंभीरता व पेचीदगी को देख फोतेदार स्वयं हरवंश सिंह के बंगले गये और वहां जमावड़े को संबोधित किया। बताते हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी में आलाकमान की राय को मानने की परिपाटी रही है और व्यापक हित में उसे स्वीकार करना ही चाहिए। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वे आलाकमान को विधायकों की इच्छा से अवगत करा देंगे। स्पष्ट है कि फोतेदार ने यह बात उफनते आवेश व आक्रोश पर छींटा मारने के मकसद से कही थी। पहले कमल नाथ चुपचाप और फिर फोतेदार विधायकों के बहुमत को संबोधित तो कर गये, लेकिन बात उसके बाद काफी देर तक नहीं बनी। तरह-तरह की दुश्चिंताएं वातावरण में अर्ध-रात्रि में तब तक तैरती रहीं, जब तक कि बूटा सिंह ने अर्जुन सिंह को बुलाकर उनसे चर्चा नहीं की। दोनों नेताओं में क्या चर्चा हुई और बूटा ने अर्जुन के कान में क्या मंत्र फूंका, कहा नहीं जा सकता, किंतु रात करीब बारह बजे औपचारिक खबर मिली कि रात में डेढ़ बजे मुख्यमंत्री आवास में विधायकों की बैठक होगी। यह बैठक लंबे चले नाटक के पटाक्षेप के तौर पर हुई। दिल्ली से आये सभी नेताओं की उपस्थिति में अर्जुन सिंह ने स्वयं मोतीलाल वोरा, जिन्होंने महज ३४४ दिन पूर्व गद्दी सौंपी थी, का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित किया और अनुमोदन शिवभानु सोलंकी ने किया। इसके बाद महज खानापूरी शेष थी, जिसके पूर्ण होते ही वोरा दूसरी बार मुख्यमंत्री बननेवाले सौभाग्यशाली राजनेताओं की पांत में शरीक हो गये।

—सुधीर सक्सेना,
एस०पी० त्रिपाठी 'आशु' के साथ, भोपाल से—

जीत की खुशी : सिंधिया, भानुप्रताप शर्मा और चंद्राकर

साक्षात्कार/**मोतीलाल वोरा**

भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा

कर्मठता और पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व में अटूट निष्ठा-मोतीलाल वोरा के व्यक्तित्व में ये दो गुण ऐसे हैं, जिन्होंने उन्हें बार-बार राजनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वोरा पहली बार नाटकीय परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने थे। उनकी विदाई भी अत्यंत आकस्मिक तरीके से, विधानसभा सत्र के दौरान, नाटकीय अंदाज में ही हुई थी। अब जब उन्होंने दुबारा प्रदेश की बागडोर संभाली, तब भी लंबी जद्दोजहद का नाटकीय दौर चला। प्रस्तुत हैं, वोरा से 'माया' की बातचीत के महत्वपूर्ण अंश :

माया : ***चुरहट लाटरी कांड में अदालत ने जो फैसला दिया है, उस पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?***

वोरा : *उच्चन्यायालय के फैसले पर अमल न करने का सवाल ही नहीं उठता। शासन कानूनी सलाहकारों से परामर्श कर समुचित कदम उठायेगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लाटरी कांड की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष एजेंसी से जांच करायी जायेगी।*

माया : ***सत्तासीन राजनेताओं पर अवैध संपत्ति अर्जन के आरोप आये दिन लगते रहते हैं। इस बारे में किसी पहल का विचार हैं?***

वोरा : *मैंने मंत्रिपरिषद में शामिल सदस्यों से कहा है कि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा मुझे दें। मैं भी अपनी संपत्ति का विवरण प्रधानमंत्री को दे रहा हूं। जहां तक भ्रष्ट आचरण की बात है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता रहा हूं, करता रहूंगा। भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार होगा और भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा।*

माया : ***विपक्षी नेता कैलाश जोशी का कहना है कि चुरहट लाटरी के घोटाले में आप भी लिप्त थे... ?***

वोरा : *ऐसा वे किस आधार पर कहते हैं?*

माया : ***उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है... ?***

वोरा : *लगता है कि उन्होंने फैसला ठीक से पढ़ा नहीं या फिर मुगालते में हैं। फैसले में स्पष्ट उल्लेख है कि मोतीलाल वोरा की इस 'स्कैंडलस और शैडी डील' में दूर-दूर तक कहीं कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसमें मेरा कहीं कोई 'रिमोट रोल' तक नहीं था। दरअसल, कैलाश जोशी गैरजिम्मेदार विपक्षी नेता की भूमिका निभा रहे हैं।*

माया : ***जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आपने और सिंधिया ने प्रदेश के खूब दौरे किये थे। क्या ये दौरे आगे भी जारी रहेंगे?***

वोरा : *बिलकुल। हम दोनों-मैं और माधवरावजी प्रदेशव्यापी दौरे पूर्ववत करते रहेंगे।*

माया : ***अर्जुन सिंह का भी कहना है कि वे दौरे करेंगे। क्या इन अलग-अलग दौरों से टकराव व विभेद नहीं पनपेगा?***

वोरा : *जब दोनों प्रधानमंत्री व कांग्रेस-इ पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार कर रहे हैं, तो टकराव कैसा? हां, गड़बड़ी तो तब होती, जब कोई इन नीतियों के खिलाफ प्रचार का रवैया अख्तियार करता।*

—सु०स०

"अपने डॉक्टर से यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र से सचमुच बालों का झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढ़िया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Dey's
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
CONTAINING PROTEIN, VITAMINS AND CO-ENZYMES
For External Use Only
Store in a cool place
100 ml.
MADE IN INDIA
DEY'S MEDICAL STORES LTD.

बालों का झड़ना रोकने का प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह श्रृंगार सामग्री नहीं है।

DMHV-4

तक बेचान नहीं किया गया है। इस्तगासे के अनुसार हजारी स्वयं पिछले काफी समय से मध्य प्रदेश की भंवरसा पंचायत समिति के पिपलिया गांव में रह रहा है। १४ दिसंबर को बेचान व रजिस्ट्री के समय वह पिपलिया गांव में ही था। इस बेचान की प्रतिलिपि लेकर जब एक व्यक्ति पिपलिया पहुंचा तब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला। उसने अपने इस्तगासे में भरत काक पर षड्यंत्र रचकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है।

इस पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने सुमरेपुर थाना प्रभारी को भरत काक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर २४ घंटे में जांच शुरू कर न्यायालय को सूचित करने के आदेश दिये। दूसरी ओर सहायक कलेक्टर, बाली उपखंड ने भी हजारी के आवेदन पर रजिस्ट्री को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी कर दी।

काक की सफाई : लेकिन जब 'माया' ने भरत काक से मुलाकात की तो, उन्होंने सारे आरोपों को सरासर झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया। मुलाकात के समय उनकी मंत्री पत्नी बीना काक भी उपस्थित थीं।

धोखाधड़ी के मुकदमे को भी सहकारी बैंक की राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बताते हुए भरत काक ने दावा किया कि यह मुकदमा ही सरासर झूठा तथा उन्हें हतोत्साहित करने के लिए दूसरे गुट की चाल है। विस्तार से बताते हुए भरत काक कहते हैं, "यह मुकदमा तो पहली ही पेशी में खारिज हो जायेगा, उलटे विरोधी गुट चार सौ बीसी के मुकदमे में फंस जायेगा, कई चेहरे बेनकाब हो जायेंगे।" भरत काक ने दावा किया कि विरोधी गुट ने हजारी को झूठ बोलकर आगे रखा और जबरन 'पावर आफ अटार्नी' पर अंगूठा लगवाया है, कोर्ट में हजारी के पेश होते ही मामला साफ हो जायेगा।

भरत काक आगे कहते हैं, "विरोधी गुट ने मुझे परेशान करने के लिए क्या नहीं किया? कोर्ट में मेरी सदस्यता तक को चुनौती दी। मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में व्यस्त कर देने की चालें चली गयीं, मुझे बदनाम करने की कोशिशें की गयीं। मेरे समर्थकों को खरीदने और धमकाने की कोशिशें की गयीं।"

अवैध रूप से पेड़ कटवाने के आरोप का खंडन करते हुए वे कहते हैं, "मैंने अपने फार्म पर ३५ हजार यूकेलिप्टस के पेड़ लगाये हैं और इसके लिए सरकारी योजनाओं में जो सामान्य प्रावधान हैं, उनका लाभ जरूर लिया है। यह लाभ मैं बीना (मंत्री) का पति नहीं होता तब भी मिलता, जैसे औरों को मिलता है। इन पेड़ों को क्रम से लगाने में जो ५०-६० पेड़ बीच में आ रहे थे, वे जरूर कटवाये हैं, पर इससे पहले एसडीओ निरंजन शर्मा से लिखित इजाजत ली गयी थी।

सारे मामले की जड़ पर प्रकाश डालते हुए भरत काक बताते हैं, "यह सब विरोधी गुट का किया-धरा है। पिछले २० साल में उनके (विरोधियों के) खिलाफ कोई लड़ा ही नहीं। मैंने पहली बार चैलेंज किया। वे चाहते थे कि किसी तरह हट जाऊं या उपाध्यक्ष का पद लेकर समझौता कर लूं। खुद सीडी देवल प्रस्ताव लेकर आया था। अब पहली बार चुनाव हुए हैं, वरना अब तक बंद कमरों में बैठकर निर्विरोध निर्णय सुना दिये जाते थे। ये लोग तो माफिया की तरह काम कर रहे थे, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठायी है।"

पति के कारण छवि पर आंच : बीना काक

> **चुनावों में अपने मंत्रिपद का दुरुपयोग करने के आरोप की सफाई में बीना काक कहती हैं, "मेरे पास क्या था दुरुपयोग करने के लिए? कला संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं किसका दुरुपयोग करती? अगर मैं अपने प्रभाव का दुरुपयोग करती तो कइयों के तो फार्म ही रिजेक्ट हो जाते।"**

बीच में बीना काक कहती हैं, "कितने दुर्भाग्य की बात है कि चुनावों में वे लोग जीत गये हैं, जो जीतने के बाद 'रूप कुंवर की जय-जयकार' के नारे लगा रहे थे।"

चुनावों में अपने मंत्रिपद का दुरुपयोग करने के आरोप की सफाई में बीना काक कहती हैं, "मेरे पास क्या था दुरुपयोग करने के लिए? कला-संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं किसका दुरुपयोग करती? अगर मैं अपने प्रभाव का दुरुपयोग करती, तो कइयों के तो फार्म ही रिजेक्ट हो जाते।"

भरत काक मुखर हो उठते हैं, "भवानीपाल सिंह (नवनिर्वाचित अध्यक्ष) की तो कुर्की निकली हुई है। नियमानुसार जिसके खिलाफ कुर्की आदेश निकले हों, वह चुनाव ही नहीं लड़ सकता। उसका तो फार्म ही रिजेक्ट हो जाना चाहिए। पर नरपत बरवड (मंत्री) ने टेलीफोन करके सिफारिश की थी। चुनावों के दौरान कई अफसरों को धमकाया गया। बैंक का स्टाफ भी उनके साथ था, उन्हें भी डर था कि सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद उनके घोटाले छुपे नहीं रह सकेंगे। और अगर ये (बीना काक की ओर इशारा करके) मंत्री हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि चुनाव न लड़ूं या सामाजिक जीवन ही त्याग दूं।"

बीना कहती हैं, "वे लोग अपने विरोध में प्रस्ताव पास होने पर प्रस्ताव की कापियां लेकर भाग गये, मीटिंग की कार्यवाही दुबारा करनी पड़ी। पर हम लोगों ने भी पाली में मजबूत ग्रुप बना लिया है। असल में यह लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ आम किसानों की लड़ाई थी। एक आम किसान के लिए आज से पहले पाली सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के चुनाव में खड़ा होना ही स्वप्न की बात थी, पर यह तो भरत के ही बूते की बात है जो लड़ लिये।"

फिर भी काक पर भूमि हड़पने का आरोप जहां का तहां है। वे परेशान भी बताये जाते हैं। कुछ लोगों का खयाल यह भी है कि मामला रफादफा कराने के लिए काक अपनी राजनीतिक पहुंच को भी आजमा रहे हैं। कुल मिलाकर पाली की स्थानीय राजनीति से पैदा हुई गुटबंदी से राज्य की राजनीति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, राज्य का मंत्रिमंडल दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। सैद्धांतिक मतभेदों ने व्यक्तिगत मतभेदों का रूप ले लिया है। सहकारी बैंक के चुनावों में सत्ता, ताकत और पैसे का जो खेल खेला गया, वह राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में अनोखा ही था। स्थानीय राजनीति में जो खेल बैंक चुनावों के नाम पर शुरू हुआ है, वह जिले की राजनीति पर दूरगामी असर दिखाने वाला है।

—धीरज कुलश्रेष्ठ

उमा शर्मा की मौत

हत्या या आत्महत्या?

जयपुर में एक प्रतिभा सम्पन्न उच्च शिक्षित महिला उमा शर्मा का शव गत दिसम्बर में एक दिन रस्सी के फंदे में झूलता पाया गया। उसके ससुर और पति इसे आत्महत्या तथा उसके पिता इसे दहेज हत्या की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के पास अपने-अपने दावों को पुष्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। कानूनी लड़ाई में उलझी इस मौत ने दो परिवारों के बीच कैसी कटुता पैदा कर दी है?

ससुराल में किसी महिला की आकस्मिक और रहस्यात्मक मृत्यु को अकसर दहेज और यातना-प्रताड़ना से जोड़ दिया जाता है। ऐसी मौत से महिला की ससुराल और मायके के बीच सहज ही एक विवाद खड़ा हो जाता है जिसका निबटारा पुलिस और अदालत करती है। ऐसे में अकसर ससुराल-पक्ष को दोषी करार दिया जाता है। किंतु बिना किसी पक्के सबूत के अथवा मृत्यु के कारण को स्पष्ट करनेवाले संदर्भों-साक्ष्यों के अभाव में, क्या ससुरालवालों को दोषी ठहराना उचित है? क्या महिला की मृत्यु का कारण उसकी अपनी मनोविकृति नहीं हो सकती? क्या ससुराल में ज्यादा प्यार-दुलार और सम्मान पानेवाली महिला (अगर भावुक हो तो) साधारण मनमुटाव या पति की मामूली अकड़बाजी पर अपनी जीवन-लीला समाप्त करने का फैसला नहीं ले सकती? क्या शिक्षित महिलायें भी ऐसी भावुकता नहीं दिखा जातीं? पिछले दिसंबर में हुई जयपुर की उमा शर्मा की अप्रत्याशित, रहस्यमयी मृत्यु ने ऐसे ही सवाल उठाये हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी को भी नहीं सूझ रहे हैं।

उमा शर्मा की अस्वाभाविक मौत ने दो परिवारों के बीच अचानक एक गहरी दरार डाल दी है। एक ओर उसके पिता बैंकुठनाथ पांडे इसे हत्या की संज्ञा दे रहे हैं तो, दूसरी ओर उसके ससुर दुर्गादत्त शर्मा इसे भावुकता तथा मानसिक डिप्रेशन (खिन्नता) में की गयी आत्महत्या बता रहे हैं। परंतु दोनों ही पक्ष अपने तर्कों के साथ कोई भी ठोस सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।

सनसनीखेज मौत: २६ वर्षीया उमा शर्मा की शादी छः वर्ष पूर्व राकेश शर्मा के साथ हुई थी। इस बीच वह एक पांच वर्षीय बच्चे नितिन की मां भी बन चुकी थी। एकाकी स्वभाव की अध्ययनप्रिय उमा अंग्रेजी व इतिहास में एमए तथा बीएड पास कर चुकी थी, इसके बावजूद वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगी रहती थी। पिछले दिनों वे राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्राथमिक परीक्षा भी पास कर चुकी थी तथा फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वे प्रायः कहा करती थी, "कुछ काम करने के लिए नौकरी करना चाहती हूं, ताकि घर पर पड़े-पड़े मोटी न हो जाऊं।" शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत उमा महिला क्रिकेट की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी थीं।

छह वर्ष के गृहस्थ जीवन में उमा ने अपने ससुराल पक्ष के व्यवहार को लेकर कभी किसी से कोई भी शिकायत नहीं की। ७ दिसंबर '८८ को प्रातः ८.१५ बजे बैंकुठनाथ पांडे ने अपने दामाद राकेश शर्मा को टेलीफोन किया ताकि उससे जायदाद संबंधी कागज के बारे में बात कर सकें। राकेश की जगह टेलीफोन पर उमा ने कहा, "आप ही घर आकर कागज ले जायें।" उमा का अप्रत्याशित उत्तर पांडे को थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर वे इस पर ज्यादा गौर नहीं कर पाये। ९.३० बजे जब पांडे आफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्हें उमा की ननद का फोन मिला कि डाक्टर को लेकर आ जायें। वे अभी कुछ समझ भी नही पाये थे कि फिर टेलीफोन आया कि सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। वे घर से निकलते, इससे पूर्व ही तीसरा टेलीफोन पहुंचा कि वे दुर्लभजी अस्पताल पहुंचें। जब बैकुंठनाथ पांडे अस्पताल पहुंचे, तो उन्होंने अस्पताल के बाहर कार में अपनी पुत्री का शव पाया। शव की गर्दन पर रस्सी का निशान बाहर से ही दिखायी दे रहा था। राकेश शर्मा ने बताया कि अस्पताल में डाक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया है।

उमा के शव को वापस लाकर दाह-संस्कार की तैयारी की जाने लगी। तभी पीछे से पांडे के मित्र लुकमान हुसैन और हरीचंद हीरावत ने जवाहर नगर थाने में फोन कर अस्वाभाविक मौत की शिकायत कर जांच के लिए कहा। पुलिस ने करीब तीन बजे मौके पर पहुंच कर लाश को अपने कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड के पास भिजवा दिया। मामले की प्रारंभिक जांच सहायक जिला नगर दंडनायक नूर मोहम्मद को सौंप दी गयी।

एक सुशिक्षित, समझदार महिला, जिसने अपनी ससुराल के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की, की इस मौत ने एक अजीब-सी उलझन पैदा कर दी है। उसके पास सबसे पहले पहुंचे राकेश शर्मा (पति) के अनुसार ७ दिसंबर की सुबह उमा ने पूजा-पाठ भी किया था। उसके बाद वे कमरे में चली गयी। करीब ९.३० बजे नीचे नये किरायेदार हीरालाल शर्मा ने कार हटाने के लिए कहा, तो राकेश को कार की चाबी लेने के लिए कमरे में जाना पड़ा, परन्तु दरवाजा बंद था। जब खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो राकेश ने जोर से धक्के दिये। इन धक्कों से दरवाजा खुल गया और राकेश ने देखा, तो सामने उमा का शरीर पंखे के कुंदे में बंधी साड़ी के सहारे हवा में झूल रहा था। तुरंत साड़ी को काटकर उमा को नीचे उतारा गया, उसे होश में लाने का प्रयास किया गया फिर अस्पताल जाने की तैयारी की गयी। उस समय पिता दुर्गादत्त भी घर पर नहीं थे, उन्हें तलाश के लिए एक दो जगह टेलीफोन भी किये गये, पर वे नहीं मिले। उमा के पिता को सूचना दी गयी। तभी खयाल आया कि डाक्टरों की हड़ताल के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल का काम ठप पड़ा है, तो दुर्लभजी अस्पताल ले जाना तय किया गया। वहां डाक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, बाद में जांच की गयी तो उमा को मृत घोषित कर दिया गया।

दोष क्या था?: उमा शर्मा (इनसेट) का शव

प्रमाण का अभाव: मजिस्ट्रेट नूर मोहम्मद ने कमरे की संबंधित सामग्री, छत का कुंडा, दरवाजे व साड़ी के टुकड़े फोरेंसिक लेबोरेट्री को जांच के लिए भिजवा दिये। अपनी जांच के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों के बयान लिये। लड़की के पिता ने अपने बयान में उमा की मौत को हत्या की साजिश बताते हुए दुर्गादत्त पर तीन लाख रुपए दहेज में मांगने का आरोप लगाया। वे कहते हैं, "मेरी बेटी इतनी भीरू

नहीं थी कि वह आत्महत्या कर ले।" पर वे शादी के छः वर्ष बाद दहेज की मांग अथवा उमा की कोई पूर्व शिकायत का ठोस प्रमाण पेश नहीं कर पाये हैं इसी तरह राकेश भी पति होने के बावजूद उमा के मानसिक तनाव और अचानक आत्महत्या कर लेने के पीछे कोई ठोस कारण बता पाने में असमर्थ हैं।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मेडिकल बोर्ड ने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे अपनी अंतिम राय फोरेंसिक तथा पैथोलोजी की रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रख कर 'हत्या' अथवा 'आत्महत्या' के प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ दिया है। दूसरी ओर अतिरिक्त जिला दंडानायक नूर मोहम्मद ने भी अपनी रिपोर्ट में मौत को संदेहात्मक बताते हुए जांच करने की सिफारिश कर इस प्रश्न से अपने को मुक्त कर लिया है।

उमा के पिता इस कांड के लिए ससुर दुर्गादत्त को पति राकेश से ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। दुर्गादत्त शर्मा राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह तथा वरिष्ठ नेता मा० आदित्येंद्र से जुड़े रहने के बाद पूर्व मंत्री बृजसुंदर शर्मा के निजी सचिव भी रह चुके हैं। आजकल दुर्गादत्त एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। 'माया' से विशेष मुलाकात में दुर्गादत्त दहेज की मांग के आरोप को झूठा बताते हुए कहते हैं, "वे (बैकुंठनाथ पांडे) कहते हैं कि मैंने तीन लाख रुपए मांगे, पर वे अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कह दें कि हमने एक पैसा भी मांगा है, बच्ची ने कभी कोई एक पत्र भी लिखा हो तो बतायें।" दुर्गादत्तजी आगे कहते हैं, "उन्हें जांच कराने का पूरा हक है। मुझे पांडेजी से कोई शिकायत नहीं है। उन्हें गुमराह किया जा रहा है। अगर डाक्टर कह दें कि यह मर्डर है, तो बिना कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा के मैं खुद सीधा जेल जाने को तैयार हूं।" डबडबायी आंखों और भरे गले से उमा की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं, ऐसी बच्ची मिल नहीं सकती। हीरे की कीमत होती है, पर उस लड़की की कीमत कोई नहीं आंक सकता। असल में लड़की तो मेरी गयी है, दिल मेरा फटा है। इस नुकसान की पूर्ति कैसे करूंगा?" वे सफायी में कहते हैं, "कोई पेशेवर हत्यारा भी अपने बच्चों को नहीं मार सकता। अगर हम योजना बनाते, तो क्या घटना की उन्हें तुरंत सूचना देते? अगर दहेज के लिए हत्या करते, तो मारने से पहले दस लाख का बीमा नहीं करवा देते?

बयानों का विरोधाभास: संयोग से जिस दिन उमा की मौत हुई थी, उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। दोनों ही पक्ष स्वीकारते हैं कि उमा बहुत भावुक लड़की थी। दुर्गादत्त कहते हैं कि पिछले दिनों वह मानसिक डिप्रेशन व तनाव की शिकार थी। परंतु वे यह नहीं बता पाते कि आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बावजूद डिप्रेशन का कारण क्या था? पढ़ी-लिखी, समझदार और जुझारू खिलाड़ी उमा अपनी कथित आत्महत्या से पूर्व कोई लिखित बयान क्यों नही छोड़ गयी?

उमा की ससुराल वालों के बयान इतने विरोधीभासी हैं कि जांच अधिकारी नूर मोहम्मद सहित अन्य लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाये। परंतु हालात और तथ्य इसे एकदम हत्या साबित करने में भी समर्थ नहीं हैं। मजिस्ट्रेट जांच के समय घटनास्थल वाला कमरा एकदम करीने से सजा व साफ पाया गया तथा आत्महत्या करने के लिए पंखे के कुंडे तक पहुंचने में काम में लाये गये कथित स्टूल व मेज दूसरे कमरे से लाकर प्रस्तुत किये गये, जिन्हें जब्त करके फोरेंसिक विशेषज्ञों के पास भिजवा दिया गया।

घटना के समय ससुर दुर्गादत्त घर पर नहीं थे। वे चार घंटे बाद घर आये। दुर्गादत्त कहते हैं कि वे अपने अधिकारी की लड़की की शादी के कार्ड बांटने के सिलसिले में गये हुए थे, उन्हें तो घर लौटने पर ही घटना के बारे में मालूम पड़ा। परंतु पांडेजी (उमा के पिता) कहते हैं कि जब दुर्गादत्त लौटे तब वे घर के बाहर बैठे थे, "दुर्गादत्त को देखते ही मैं उनके पैरों में गिरकर रोने लगा, परंतु दुर्गादत्त न तो चौंके, न रुके और न ही पूछा कि इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं। वे सीधे चुपचाप ऊपर चले गये। सास कौशल्या देवी बताती हैं, दुर्लभजी अस्पताल में मेरे कहने पर डाक्टरों ने उमा को आक्सीजन दी तथा एक इंजेक्शन भी लगाया।" परंतु वे उस निजी अस्पताल की कोई पर्ची या बिल प्रस्तुत नहीं करतीं। दूसरी ओर अस्पताल के डाक्टर और रिकार्ड भी उमा शर्मा के कथित इलाज से इनकार करते हैं।

पिता बैकुंठ पांडे पहले दिन दहेज का जिक्र नही करते हैं, पर तीसरे दिन बयान दर्ज करवाते समय अचानक तीन लाख मांगने व न देने पर लड़की की हत्या कर देने का आरोप लगाते हैं। पर इससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते और न ही शादी के छः साल बाद दहेज की मांग का तर्क प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर कौशल्या देवी कहती हैं, "हमने उनका एक भी पैसा न तो मांगा और न ही रखा, सगाई के समय जो ग्यारह हजार रु० दिये थे, उनमें भी हमने दस हजार रु० और मिलाकर बैंक में उमा के नाम से जमा करा दिये थे, जो आज भी जमा हैं।"

पति: राकेश शर्मा

ससुर: दुर्गादत्त शर्मा

> **"अगर दहेज के लिए हत्या करते, तो मारने से पहले दस लाख का बीमा नहीं करवा देते।"**

इस मामले के अखबारों में छपने के बाद घबराये ससुराल पक्ष ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दे डाली जो इस आधार पर खारिज हो गयी कि जांच पूरी होने से पूर्व अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। सामाजिक दबावों के कारण मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट भी आमतौर की अपेक्षा जल्दी प्रस्तुत कर दी गयी, इस पर दुर्गादत्त शर्मा ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर जाच की कार्यवाही इंटेलीजेंस (गुप्तचर) विभाग के पास स्थानांतरित करवा दी, जहां आईपीएस लियाकत अली इस घटना की जांच कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब लड़के वालों ने दबाव डालकर जांच स्थानांतरित करवायी हो। यह संभावित गिरफ्तारी की आशंका से मुक्ति पाने के लिए किया गया। कुल मिलाकर इस मामले में डाक्टरों के बोर्ड से लेकर जांच अधिकारी तक अपनी कोई दोटूक राय देने से कतरा रहे हैं और अपने अंतिम निर्णयों को फोरेंसिक परीक्षण के परिणाम आने तक के लिए सुरक्षित रखा है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होने के बावजूद पुलिस विभाग ने डेढ़ माह बाद तक सारी सामग्री 'फोरेंसिक लैब' को नहीं भिजवायी है।

दांपत्य का तनाव: मामले की जांच-पड़ताल से जो अतिरिक्त तथ्य सामने आये हैं, वे इस घटना के कारणों को ज्यादा सफायी से उजागर करते हैं। पता चला है कि उमा शर्मा को सात सप्ताह का गर्भ था और इसे लेकर पति-पत्नी के बीच तनाव चल रहा था। खुद पति राकेश शर्मा स्वीकारते हैं कि घटना की पूर्व रात वे ठीक से सो नहीं पाये थे। उनकी आंख असामान्य रूप से प्रातः ३ बजे ही खुल गयी थी। सुबह-सुबह उठकर उन्होंने आफिस का काम निबटाया। सुबह ६ बजे के बाद वे वापस बेडरूम में नहीं गये, ८ बजे तक ऊपर छत पर रहे। नीचे उतरे तो उमा ने चाय पीने के लिए कमरे में चलने को भी कहा, परंतु राकेश ने अनिच्छा जाहिर कर दी। इस पर उमा ने एक दो बार बुशर्ट व पजामा पकड़ कर खींचा। परंतु राकेश ने मूड न होने की बात कह दी। इसके बाद उमा ने कमरा बंद कर लिया।

दांपत्य जीवन के इस कथित तनाव के समुचित कारण भी राकेश नहीं बताते। परंतु घटना पर दिमाग लड़ाने वाले अधिसंख्य लोग मानते हैं कि उमा के तनावग्रस्त होने तथा राकेश के सो न पाने की यह घटना ही संभवतः इस मौत की जिम्मेदार है जिसे दोनों ही पक्ष छिपाना चाहते हैं।

लेकिन इस सबके बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि उमा ने आत्महत्या क्यों की? इस मजबूरी के क्या कारण थे? अगर हत्या हुई है, तो अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? परंतु इससे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हर बहू की रहस्यमय मृत्यु दहेज-हत्या ही होती है? और अगर बहुओं को ससुराल में आत्महत्या करनी पड़े, तो भी क्या संबंधी पक्ष को दोषमुक्त माना जा सकता है?

—ओम सैनी, धीरज कुलश्रेष्ठ के साथ

जनता दल की रैली

मुलायम सिंह का शक्ति-प्रदर्शन

जनता दल के विभिन्न घटकों के असहयोग के बावजूद गत १९ जनवरी को कानपुर में हुई मुलायम सिंह यादव की विशाल रैली को देवीलाल और चंद्रशेखर ने संबोधित किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा अजीत सिंह ने अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या कारण है कि ये सभी नेता मुलायम सिंह को इस रैली में मिले ५१ लाख रुपए की थैली को मनमाने ढंग से खर्च करने की आजादी देने के लिए बाध्य थे। इतना ही नहीं, देवीलाल ने अपनी ओर से मुलायम सिंह को २९ लाख रुपए और दिये। मुलायम सिंह को इस रैली के बाद उत्तर प्रदेश में जनता दल का सबसे सशक्त नेता क्यों माना जा रहा है?

रैलियों के माध्यम से जनशक्ति और थैलियों के जरिये धनशक्ति का प्रदर्शन कर के मुलायम सिंह यादव ने खुद को उत्तर प्रदेश का प्रबलतम विपक्षी नेता सिद्ध करने का प्रयास किया है। जनता दल के सभी घटकों के असहयोग के बावजूद यादव ने १९ जनवरी को कानपुर के फूलबाग में आयोजित रैली में एक लाख से अधिक भीड़ जुटाकर अपनी हैसियत का अहसास करा दिया। इस रैली में मुलायम सिंह समर्थकों ने पूरे राज्य से एकत्रकर उन्हें ५१ लाख रुपए की थैली दी। रैली-थैली की इस सियासत का नतीजा यह रहा कि उत्तर प्रदेश में जनता दल में चल रही गुटबाजी और भी मुखर हो उठी है।

जनता दल में खुलेआम चल रहे इस घटकवाद का एक ही कारण है—राज्य जनता दल का अध्यक्ष पद। हर घटक का नेता यही चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उसे ही मिले, ताकि देश की राजनीति के भाग्य का फैसला करनेवाले इस सबसे बड़े सूबे के सहारे वे भविष्य में अपने मंसूबे साकार कर सकें। इसी राजनीति के चलते जनता दल के केंद्रीय नेताओं ने भी अपने-अपने घटक को पूरी छूट दे रखी थी।

थैली पर विवाद: मुलायम सिंह यादव को मिलनेवाली ५१ लाख रुपए की थैली को जनता दल के लोकदल (अजीत सिंह), जनता पार्टी और जनमोर्चा घटकों ने विवाद का मुद्दा बनाया। इस विवाद को हवा देनेवालों में प्रदेश जनता पार्टी अध्यक्ष मनोहर लाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यपाल सिंह यादव ने सक्रिय भूमिका निभायी। इन लोगों का कहना था कि मुलायम सिंह को रैली में मिली थैली जनता दल के केंद्रीय कोष में दे देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता दल के नाम पर यह धन एकत्र किया है। इसके जवाब में स्वयं मुलायम सिंह यादव का कहना था, "जनता दल के गठन के पूर्व ही इस रैली के आयोजन की घोषणा कर दी गयी थी, अतः इस धन पर जनता दल का कोई अधिकार नहीं बनता है।" मुलायम सिंह के दाहिने हाथ समझे जानेवाले बाराबंकी के विधायक तथा जनता दल के प्रभावी नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने 'माया' से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, "हमने इस रैली का आयोजन मई, १९८८ में ही तय कर लिया था। उस समय जनता दल गर्भ में भी नही था। मुलायम सिंह यादव की संघर्षमय राजनीतिक यात्रा के लिए उन्हें इस प्रकार सम्मानित करने का फैसला किया गया था।"

सचाई भी यही है कि मुलायम सिंह यादव के लिए जुटाई गयी ५१ लाख की रकम सिर्फ उन्हीं के गुट के लोगों ने गांव-गांव जाकर एकत्र की थी। जब यह विवाद जोर पकडने लगा, तो दिल्ली में वीपी सिंह, अजीत सिंह, रामविलास पासवान और शरद यादव ने आपस में बैठकर विचार-विमर्श किया और मुलायम सिंह यादव को पूरा अधिकार दे दिया कि वे कानपुर में मिलनेवाली थैली का उपयोग अपने विवेक से सार्वजनिक जीवन में जिस तरह चाहें, कर सकते हैं। जनता दल के वरिंष्ठ नेताओं के निर्णय के बावजूद उत्तर प्रदेश में उठापटक चालू रही। मुलायम सिंह यादव ने भी १७ जनवरी को यह घोषणा कर अपने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया कि कानपुर में मिलनेवाले ५१ लाख रुपए का उपयोग वे 'किसान ट्रस्ट' बनाने में करेंगे। दूसरी ओर हेमवती नंदन बहुगुणा ने भी मुलायम सिंह यादव की रैली को विफल करने की जोड़तोड़ शुरू कर दी थी। बहुगुणा १६ जनवरी से ही लखनऊ में आकर जम गये थे। साथ ही उन्होंने फरवरी के तीसरे सप्ताह में कानपुर में वामपंथी दलों सहित नवगठित राष्ट्रीय अभियान समिति की रैली की घोषणा भी कर दी। वास्तव में बहुगुणा ने इसके पूर्व २३ दिसंबर, १९८८ को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में जो रैली की थी, उसकी सफलता का एक कारण यह भी था कि जनता दल में शामिल मुलायम सिंह विरोधी भी बड़ी संख्या में वहां आ जुटे थे।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (अजीत सिंह गुट) रामनरेश यादव और विधायक मनोहर लाल ने भी रैली को विफल करने की कोशिशें जारी रखीं। ५ जनवरी को इटावा में मुलायम सिंह यादव द्वारा आयोजित रैली की सफलता के बाद से इन लोगों को राज्य जनता दल में मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व बढ़ता नजर आने लगा था। उधर अजीत सिंह रामनरेश यादव या राजेन्द्र सिंह में से किसी एक को प्रदेश जनता दल का अध्यक्ष निर्वाचित करवाकर राज्य में अपनी पकड़ अधिक मजबूत बनाने की राजनीति खेल रहे थे। इसी कारण कानपुर शहर में मुलायम सिंह यादव की इस रैली का न तो प्रचार हुआ और न ही कानपुर की भागीदारी भीड़ जुटाने

देवीलाल का वरदहस्त: मुलायम सिंह और देवीलाल

छाया: मनमोहन शर्मा

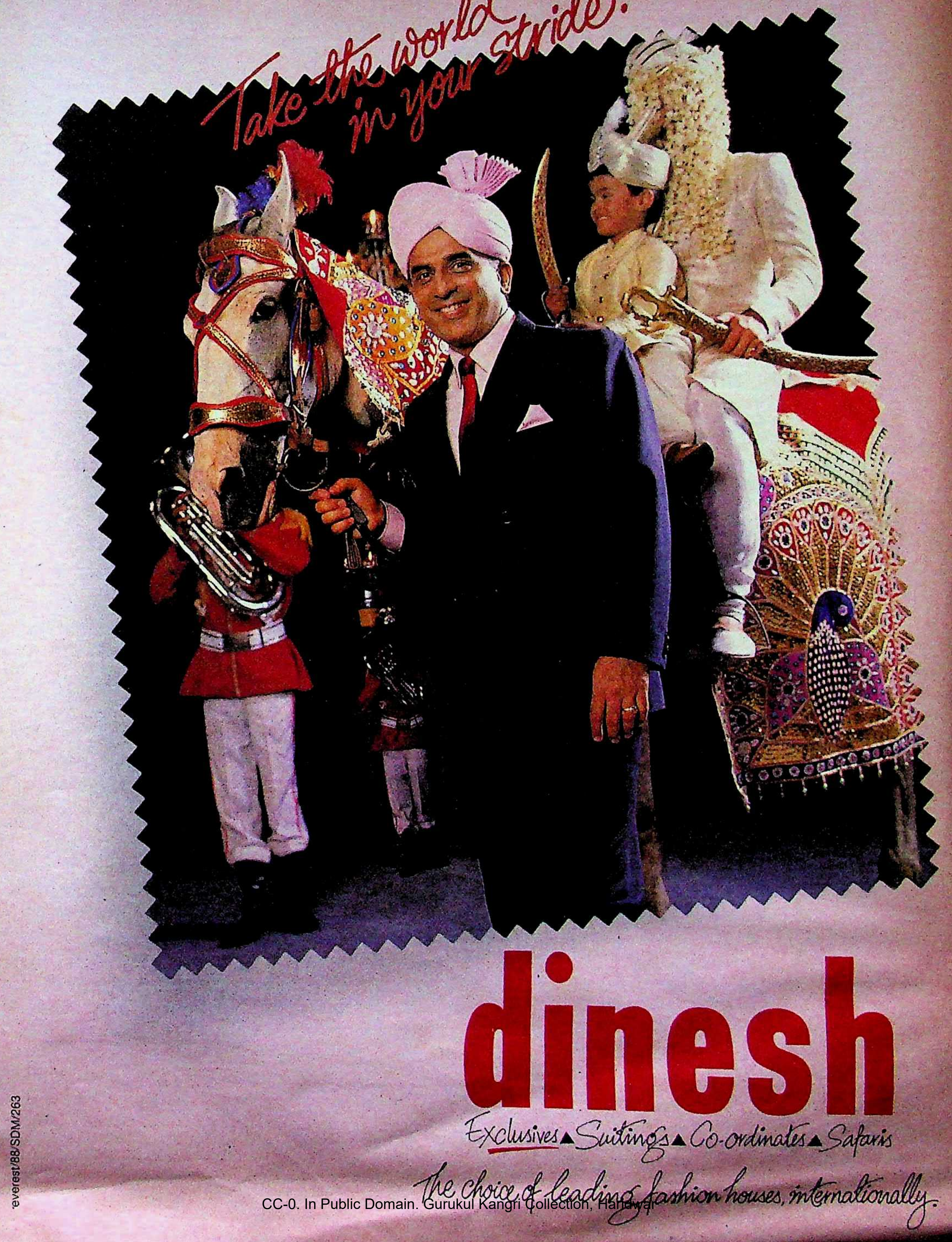
Take the world in your stride.
dinesh
Exclusives ▲ Suitings ▲ Co-ordinates ▲ Safaris
The choice of leading fashion houses, internationally.
everest/88/SDM/263

घाटी का सुंदर संसार

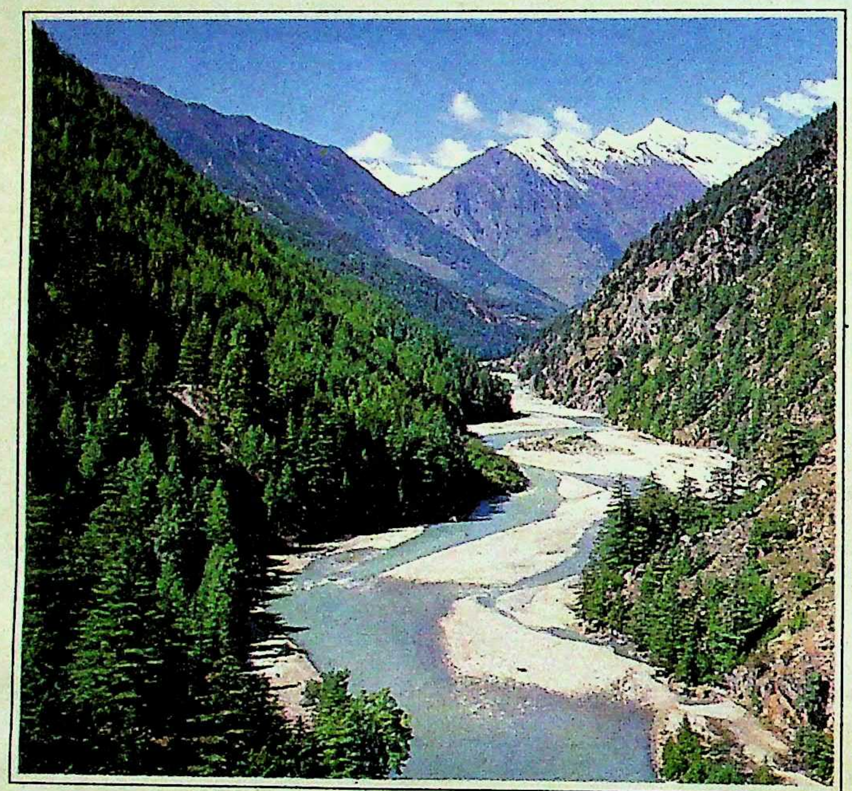

ऊपर. और ऊपर.

पहाड़ों की गोद में खिलखिलाती फूलों भरी घाटियों का सफ़र.

रास्ते में ऊंचे दर्रों का जादुई सौंदर्य.

चारों ओर आसमान भेदते शिखर और पर्वत श्रृंखलाएं जहां प्रकृति का अनंत राज्य है.

लेकिन वादियों की हमारी यात्रा जहां से शुरू हुई, वहां लगा था कूड़े का ढेर.

और फिर पहाड़ तो जैसे कचरे के अंबार बने थे.

यह उन निर्दय सैलानियों का काम था जो हमसे पहले यहां आये.

दुखद बनी राह

डट कर छुट्टी मनाने आये सैलानी जाते-जाते पहाड़ों को सौंप गये अपनी गंदगी के निशान : सड़ता हुआ खाना, ख़ाली डिब्बे, टूटी हुई बोतलें, फटे हुए जूते और झील में सड़ांध फैलाते ढेरों छिलके.

यह धरोहर आपकी है इसे बचाइए

यात्रा सिर्फ़ सैर नहीं, एक खोज भी है.

भारत की अनमोल विरासत : समूची दुनिया में बेजोड़.

पर्यटन विभाग भारत सरकार

पहाड़ पर कूड़े का अंबार

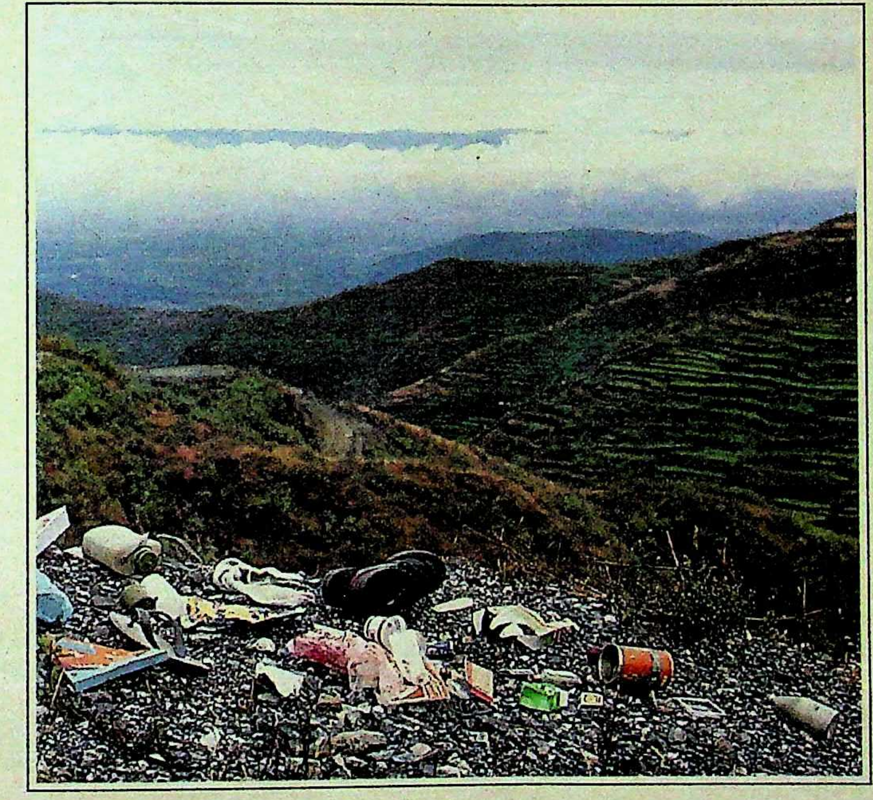

अनगिनत क़िलों, स्मारकों, तीर्थों में गूंजती हुई 5 हज़ार साल की गौरव-गाथा.

और विविधता और वैभव से भरी प्रकृति.

कितने ही रंग और रंगतों में मोहती.

कोई किसी स्मारक को बदशक्ल करता दिखे, किसी पूजास्थल या तीर्थ का अपमान करे या अपने माहौल को बिगाड़ता गंदा करता नज़र आये तो आप चुप न बैठिए.

उसे समझाइए.
उसे रोकिए.
उसकी शिकायत कीजिए.
अपनी अनमोल विरासत को बचाइए.
यही है आपकी धरोहर.

हम ही रचेंगे
हम ही रखेंगे
अपना भारत सुन्दर

Department of Tourism Government of India

HTA 6241 HIN

RILAXON
आराम
सहारा
स्वास्थ्य
गहरी नींद का मजा
रोज सुबह बिल्कुल तरोताजा
Moon moon Sen
(मुनमुन सेन)

हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति है—हमारा शरीर। हमारे टहलने, उठने, बैठने और यहाँ तक कि जिस पर हम सोते है, उस पर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य ।
सुख की नींद के माने ही है सही मैट्रेस पर सोना ।
रिलैक्साँन के मैट्रेस, तकिये, कुशन वैज्ञानिक ढंग से प्राकृतिक कोयर एवं लैटेक्स से बने हैं जिससे आपकी भरपूर **सहारा** एवं **आराम** मिलता है ।

रिलैक्साँन जीवन भर आपकी हर रात को बनाए शुभरात्रि—निश्चिंत और आरामदेह रात्रि ।

RILAXON
आपके आराम के लिए
मैट्रेंस ● कुशन ● तकिया ● अन्डर ले

श्री दिग्विजय सिमेन्ट कों. लि.
कोयर और फेल्ट डिविजन
१४ नेताजी सुभाष रोड
कलकत्ता-७०० ००१

ISI 8391-1977

Sobhagya(c)/RIL/3/89/HIN

सुब्रह्मण्यम स्वामी का खेल

मूल्यों की राजनीति के लिए सराहे गये समाजवादी नेता रामकृष्ण हेगड़े के खिलाफ विवाद की राजनीति करने वाले डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की नयी मुहिम और मुखरता का असली सबब क्या है ?

भारतीय राजनीति के 'उद्दंड बालक' डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी एक बार फिर अपनी ही पार्टी के दिग्गजों की पाक-साफ छवि को धूल-धूसरित और ध्वस्त करने के पसंदीदा खेल में जुटे प्रतीत होते हैं। लक्ष्य इस बार नवगठित जनता दल के उपाध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े हैं। स्वामी द्वारा उजागर किये टेलीफोन टेप कांड के कारण हेगड़े को मुख्यमंत्री की कुरसी ही खाली करनी पड़ी थी। दोनों ही महारथी पिछले महाभारत को अभी भूले भी नहीं थे कि एक बार फिर आमना-सामना हो गया है।

स्वामी का वर्तमान आरोप यह है कि रामकृष्ण हेगड़े ने अपने साढ़े पांच साल के मुख्यमंत्रित्वकाल के दौरान बंगलौर की १० हजार एकड़ बेशकीमती जमीन के घोटालों से अपने परिवारजनों को ३५० करोड़ रुपए का नाजायज लाभ पहुंचाया है। इस कार्य में उन्होंने कंपनी कानून और फेरा के २७ नियमों का उल्लंघन किया है। अनेक धांधलियों के आरोपों के अतिरिक्त पुष्टि के लिए पेश अनेक दस्तावेजों के साथ स्वामी भारत तथा कर्नाटक सरकार से मामले की छानबीन और हेगड़े के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

जाहिर है कि आरोपों और अपमान का यह कड़वा घूंट हेगड़े आसानी से पीनेवाले नहीं। विशेषकर इसलिए कि रामकृष्ण हेगड़े आज तक मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते रहे हैं और अपने पाक-साफ होने का दावा भी। आरोपों को काल्पनिक और बेबुनियाद बताते हुए हेगड़े ने कहा है कि न तो एक इंच जमीन बेची गयी है और न ही मेरे परिवार ने कभी कोई फायदा उठाया है। डा० स्वामी को 'पेशेवर ब्लैकमेलर' करार देते हुए, उन्होंने कहा, "स्वामी ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। हर उस हाथ को काटा है, जिसने उन्हें पुचकारा और खाना खिलाया है। सबसे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर आरोप लगाये, जिन्होंने उन्हें जनसंघ में लाकर सांसद बनवाया। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर पर हमला बोला, जिन्होंने उन्हें जनता पार्टी का टिकट दिया और महासचिव बनाया। अब मेरे पीछे लग गये हैं।"

थाने में चोर : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी

बात जब स्वामी के कानों तक पहुंची, तो वे बोले, "मैं किसी को तभी ब्लैकमेल कर सकता हूं, जब उसने कोई घोटाला किया हो या कुछ छुपा रहा हो। रहा दूसरी बात, सो न तो हेगड़े ने मुझे कभी पुचकारा है, न खाना खिलाया है। चंद्रशेखर से मेरा वैचारिक मतभेद अवश्य हुआ था, किंतु आज हम दोनों पुनः साथ हैं जो यह सिद्ध करता है कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। मैंने तो चरण सिंह और मोरारजी भाई जैसे कठिन और कठोर व्यक्तित्व-वाले नेताओं से निभाया है।"

क्या हेगड़े दोषी हैं ? : आरोपों-प्रत्यारोपों की नित नयी बाढ़ के बीच दो प्रमुख प्रश्न उठते हैं। सर्वप्रथम यह कि क्या सचमुच घपले हुए ? और यदि हुए, तो कौन कितना दोषी है ? हेगड़े के सम्मुख प्रश्न फिलहाल, कर नहीं तो डर कैसा, का है। यदि वे सचमुच पाक-साफ हैं, तो न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया शीघ्र ही दूध-का-दूध व पानी-का-पानी कर देगी। अदालत और जनमत दोनों को ही अपने-अपने ढंग से फैसला देने का हक भी रहेगा और मौका भी। बात तभी गंभीर रूप धारण करेगी, जब हेगड़े दोषी पाये जायेंगे, क्योंकि उस समय विपक्ष राजीव सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध उंगली और आवाज उठाने के अधिकार को लेकर निश्चय की सांसत में पड़ जायेगा।

यही भावी परिदृश्य दूसरा अहम सवाल उठाता है। प्रश्न यह है कि राजीव सरकार हटाने के जाने-माने विपक्षी लक्ष्य को छोड़ स्वामी अपने ही वरिष्ठ नेता को कठघरे में खड़ा कर, सरेआम नंगा करने पर क्यों उतारू हैं ? साथ ही यह कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था ?

हेगड़े-स्वामी के झगड़ों को प्रारंभ से देखने-झेलनेवाले एक जनता सांसद ने 'माया' को बताया कि शुरू में दोनों के मध्य झगड़ा चंद्रशेखर को लेकर बढ़ा। उन दिनों चंद्रशेखर-स्वामी में ठनी थी और हेगड़े चंद्रशेखर के साथ थे। यह दूसरी बात है कि आज समीकरण ठीक विपरीत हैं। बदले का मौका स्वामी को हेगड़े के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाये जाने के प्रश्न पर मिला। स्वामी ने चंद्रशेखर के प्रस्ताव का भरपूर विरोध किया। हेगड़े तो गद्दीनशीं हो गये, पर चंद्रशेखर-स्वामी झगड़े के चलते स्वामी पार्टी से निष्कासित कर दिये गये। मजे की बात यह है कि इसमें भी स्वामी ने चंद्रशेखर से अधिक हेगड़े को दोषी ठहराया।

तनाव बना रहा। इस बीच विपक्ष में कई समीकरण बने और बिगड़े। १९८७ के अन्त में विपक्षी एकजुटता के चलते चार दलों—जनता, कांग्रेस-स, लोकदल-अ, जनमोर्चा—का राष्ट्रीय मोर्चा बना; जिसमें स्वामी ने महती भूमिका निभायी। बकौल स्वामी यह हेगड़े को रास न आया। उन्होंने मार्ग रोकने का हर संभव उपाय किया, पर दाल न गली। इसके तुरंत बाद हुए ज़नता-लोकदल-अ के विलय ने तो बवंडर खड़ा कर दिया। जनता पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि विलय संबंधी हेगड़े गुट का विरोध विलय के मुद्दे पर उतना नहीं था, जितना कि इस रोष के कारण कि न केवल स्वामी को इसके द्वारा जनता पार्टी में पिछले दरवाजे से प्रवेश ही मिला था, बल्कि उसका श्रेय भी अधिकांशतः स्वामी के खाते में जा रहा था।

गुटबंदी के चलते स्वामी चंद्रशेखर—अजीत गुट के साथ तो रहे ही, टेलीफोन टेप कांड को उजागर कर हेगड़े को पदच्युत करने में भी सफल रहे। हेगड़े के लिए बदले की आग में जलना स्वाभाविक रहा।

मौका उनको जनता दल के गठन के समय मिला। स्वामी के अनुसार, "हेगड़े विश्वनाथ प्रताप सिंह के कान भरने और उनके मार्ग में रोड़े अटकाने के काम में ही अधिक व्यस्त रहे, क्योंकि हेगड़े अपने को दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी जाननेवाला नेता सिद्ध करने में लगे रहे हैं। इसमें मैं उन्हें प्रतिद्वंद्वी दिखायी देता हूं। वैसे भी मैंने उन्हें कभी इज्जत व अहमियत नहीं बख्शी है, क्योंकि उनमें

मैं किसी को
तभी ब्लैकमेल कर सकता हूं,
जब उसने कोई
घोटाला किया हो या कुछ
छुपा रहा हो।

—सुब्रह्मण्यम स्वामी

अच्छे चारित्रिक गुण नहीं, वे पूरे फ्राड (धोखा) हैं।"

यद्यपि स्वामी हेगड़े विरोधी दस्तावेजों की प्राप्ति का दिन १६ दिसंबर, १९८८ बताते हैं, किंतु 'माया' को विश्वसनीय सूत्रों से स्वामी के पास अन्य हेगड़े विरोधी दस्तावेजों का समाचार टेप कांड के कुछ दिनों बाद ही मिला था। स्वामी निश्चय ही उपयुक्त समय और मौके की तलाश में थे।

स्वामी पर अविश्वास: तमिलनाडु चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कषगम से सीटों के तालमेल बनाने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वामी को सौंपा था, क्योंकि उनकी और करुणानिधि की मित्रता जगजाहिर है। स्वामी के अनुसार सिंह ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें भी मद्रास साथ चलना चाहिए, तो उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी अध्यक्ष के नाते यह उन्हें शोभा न देगा. लेकिन मद्रास जाने के लिए जब स्वामी हवाई जहाज में सवार हुए, तो सिंह को भी वहां देख उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्वामी पर विश्वास न करने और स्वयं साथ जाने की सलाह विश्वनाथ प्रताप सिंह को किसी अन्य ने नहीं, स्वयं हेगड़े ने दी थी। स्वामी को अपमान का घूंट पीना पड़ा। पर पानी तब सिर से गुजर गया—जब जनता दल के पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर हेगड़े स्वामी को कहीं कोई पद न देने पर हठ कर बैठे और इसमें अजीत सिंह व चंद्रशेखर की भी न चली। हारने के लिए स्वामी के पास कुछ विशेष था नहीं। हेगड़े के पास बहुत कुछ था। स्वामी ने उसी पर सीधा वार करने की ठान ली। उन्होंने कुछ दिन तक मुद्दों, तरीकों और धमकियों का सहारा लिया, फिर प्रेस-कान्फ्रेंस में आरोपों-दस्तावेजों की भरमार कर हेगड़े की छीछालेदर कर देने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी।

स्वामी के विचारों और कार्यशैली से परिचित एक जनता सांसद ने 'माया' को बताया कि स्वामी विवाद की राजनीति में अधिक विश्वास रखते हैं, सेवा की राजनीति में कम। स्वयं स्वामी ने कहा, "मैं वैचारिक आधार को अधिक महत्व देता हूं और महात्मा गांधी के उस सिद्धांत में विश्वास रखता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कस्बों व राज्य के स्तर के नेताओं का जमीन से जुड़ना उतना ही आवश्यक है, जितना राष्ट्रीय नेताओं का विचारों (आइडियोलाजी) से।"

"विवाद के अतिरिक्त स्वामी प्रचार के चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक अत्यन्त भूखे हैं। येनकेनप्रकारेण सुर्खियों में बने रहना स्वामी की सबसे बड़ी जरूरत भी है, कमजोरी भी," यह टिप्पणी की हेगड़े गुट के जाने-माने सांसद ने। कथन की पुष्टि में उन्होंने कुछ समय पूर्व मोरारजी देसाई के पूर्व प्रेस सचिव गौतम भार्गव के उस लेख का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रचार की इच्छा उनमें इतनी अधिक प्रबल है कि किसी शादी के मौके पर उनका बस चले, तो आकर्षण का केंद्र-बिंदु बनने के लिए स्वयं दूल्हे का स्थान ही ले लें। मुर्दनी में इसी कारण मुर्दे का स्थान लेने में भी वह आगे रह सकते हैं।" स्वामी उलट कर कहते हैं, "राजनीति में प्रचार का भूखा कौन नहीं? जो नेता इससे इनकार करता है, वह महा ढोंगी है।"

स्वामी के अनुसार, उनकी वर्तमान हेगड़े—(विपक्ष) विरोधी मुहिम विपक्ष के ही हितों की रक्षा करने से प्रेरित है। खासकर इसलिए कि समय रहते विपक्ष में साफ-सफाई हो जाये और ऐन चुनाव के समय कांग्रेस भंडाफोड़ कर लाभ न उठा सके। अगर विपक्ष केवल सत्तारूढ़ का भ्रष्टाचार उजागर करेगा, अपने भ्रष्टाचार के प्रति आंख मूंदे रहेगा, तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जायेगा और लोग कहेंगे कि सभी राजनीतिक चोर हैं। अतः विपक्ष को भ्रष्टाचार के बारे में दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए।

दोहरे मापदंड के प्रश्न पर ही स्वामी विश्वनाथ प्रताप सिंह से भी रुष्ट हैं। स्वामी के अनुसार हेगड़े के विरुद्ध दस्तावेज मिलते ही, उन्होंने सिंह को उसकी जानकारी दी थी। पर सिंह के कुछ न करने पर उन्हें भंडा फोड़ना ही पड़ा। 'माया' से उन्होंने कहा, "जनता दल के गठन के समय बंगलौर सम्मेलन में स्वयं हेगड़े ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को चोर पकड़नेवाला थानेदार बताया था। पर बाहर जाकर चोर पकड़ने से पहले क्या यह आवश्यक नहीं कि थाने में मौजूद चोरों को पकड़ा जाये?"

कांग्रेस-एजेंट की छवि: हेगड़े के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह का अप्रत्यक्ष शिकार करने के कारण स्वामी में कांग्रेस एजेंट की झलक दिखायी देती है। हेगड़े समर्थक एक नेता ने कहा कि कांग्रेस ही उन्हें समस्त दस्तावेज व सुविधा मुहैया करा अपना उल्लू सीधा कर रही है। एक अन्य ने उन्हें सन १९८० से ही कांग्रेस का एजेंट बताया। अतः प्रश्न उठता है कि जानकारी होते हुए भी विपक्ष ने उन्हें अपने बीच, वह भी किसी-न-किसी बड़े ओहदे पर क्यों रखा? जहां तक दस्तावेजों का संबंध है, कर्नाटक में असंतुष्ट नेताओं और अधिकारियों की लम्बी कतार जगजाहिर है। उनके द्वारा दस्तावेज मुहैया कराया जाना अधिक तार्किक लगता है और यही स्वामी का कहना भी है।

चंद्रशेखर की भूमिका: कांग्रेस का ही नहीं, स्वामी की हाल की कारगुजारियों में चंद्रशेखर का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। चंद्रशेखर के निकट सूत्र इसे अस्वीकार करते हैं। एक ने बताया कि चंद्रशेखर अत्यन्त क्षुब्ध और रुष्ट हैं, क्योंकि करता कोई है, दोष उनके सिर-माथे जाता है। पर इस समय वे कुछ करने में असमर्थ हैं। मुंह में कौर ऐसा है जो न उगलते बनता है, न निगलते।

स्वामी की हेगड़े विरोधी मुहिम के साथ जनता पार्टी के एक छोटे गुट के जनता दल विरोध को जोड़ने से परिदृश्य ही बदल जाता है। हाल की समस्त उठापटक को नजदीक से देखने-समझनेवाले एक पर्यवेक्षक के अनुसार, "जनता पार्टी को जीवित रखने की मुहिम और हेगड़े विरोध जुड़े हुए मुद्दे हैं। मुख्य लक्ष्य एक ओर कार्यकर्ताओं में दुविधा और असंतोष फैलाना है, दूसरी ओर नाम और चुनाव चिह्न के मुद्दे पर जनता दल को सांसत में डालना है। अधिकांश काम इस बिना पर किये जा रहे हैं कि राज्य और जिला स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति के समय जनता दल में हायतोबा मचना अपरिहार्य है। यदि अलग एक दुकान खुली रहेगी, तो असंतुष्ट उसमें आ जायेंगे।"

नतीजे बुरे होंगे, इसे कोई नकार नहीं सकता। हेगड़े की सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त था, यह कर्नाटक से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है। जब तक बात ढकी-मुंदी थी, तब तक चिंता की कोई बात नहीं थी। अब चर्चा सरेबाजार होने का खतरा भी सामने आ गया है। हेगड़े की समस्या यह है कि आरोप गुंडूराव पर लगे होते, तो बात कुछ और होती। हेगड़े तो मूल्यों पर आधारित उच्चस्तर की निष्ठा के मुद्दे पर ही कद्दावर नेता बने हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पैरों तले से तो जमीन के ही खिसक जाने की आशंका है, क्योंकि पिछले दो वर्षों से वे जिस भ्रष्टाचार को राजनीति का मुद्दा बनाकर चल रहे थे, उसकी छाया जनता दल पर भी पड़ने लगी है। विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न का खमियाजा केवल उन्हें ही नहीं, समस्त विपक्ष को उठाना पड़ेगा और लाभ निश्चय ही कांग्रेस को प्राप्त होगा। इस दृष्टि से सुब्रह्मण्यम स्वामी कांग्रेस के एजेंट नहीं, तो उसके सबसे बड़े हितैषी अवश्य सिद्ध होंगे।

—रंजना कक्कड़

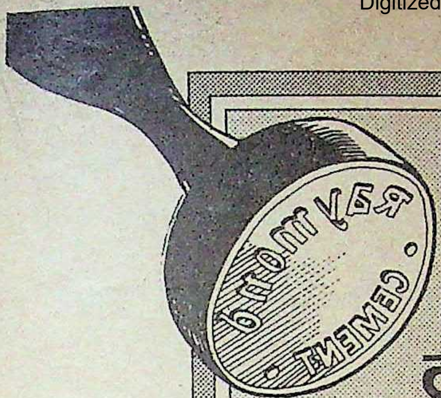

जब किसी निर्णय पर सालों-साल साथ निभाने की बात निर्भर हो तो ठोस प्रमाण उसमें मदद करते हैं

प्रमाण १ : गुणवत्ता
रेमण्ड का नाम ही सर्वोच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय है.

प्रमाण २ : मज़बूती
बी आइ एस के मानकों से निश्चय ही ज़्यादा 'कॉम्प्रेसिव' शक्ति.

प्रमाण ३ : ब्लेन
महीनतम ब्लेन के कारण अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मनचाही मज़बूती की गारंटी.

प्रमाण ४ : जमाव गुण
रेमण्ड सीमेंट पूर्ण जमाव का आश्वासन देता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव की अवधि बी आइ एस मानकों से बेहतर है.

प्रमाण ५ : विक्रेताओं का जाल
देशभर में रेमण्ड के अधिकृत विक्रेताओं का जाल शत प्रतिशत असली सीमेंट उपलब्ध कराता है.

प्रमाण ६ : पैकेजिंग
स्वचालित रोटरी पैकेजिंग मशीनों द्वारा सबसे मज़बूत प्लास्टिक और जूट की बोरियों में पैक याने निकाल लिए जाने का अंदेशा ही नहीं.

प्रमाण ७ : बचत
कोई अन्य सीमेंट हर बार इतने ठोस लाभों की गारंटी दे नहीं सकते.

प्रमाण ८ : हमारे कुछ ग्राहक
एन टी पी सी, ऑयल इंडिया लि., भारतीय रेलवेज़, वायजैक़ स्टील प्लांट, ईस्ट इंडिया होटल्स लि., आइ टी सी लिमिटेड, वोल्टास लि., टाटा रोबिन्स फ्रेसर, निटको टाइल्स, अंसल हाउसिंग प्रा. लि., एस.आर.एफ. निप्पॉन डेनरो इस्पात लि. जी.ई.सी.

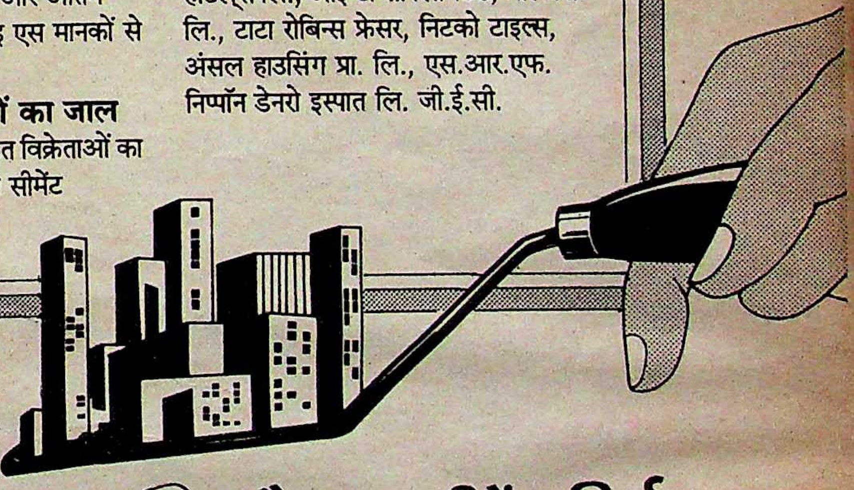

कैलाश सीमेंट : निर्माता

रेमण्ड

गुणवत्ता का दूसरा नाम.

हिरोहितो का निधन

जापानी साहस को चुनौती

सम्राट हिरोहितो के निधन के साथ ही जापान एक दोराहे पर पहुंच गया है। दिवंगत सम्राट से जुड़ी दूसरे महायुद्ध में पौने पांच करोड़ लोगों की मृत्यु की त्रासद याद ने जहां विश्व का जख्म हरा कर दिया है वहीं जापान में राजशाही खतम करने की आवाज भी तेज हो गयी है। ऐसे में जापान का मौजूदा शासन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर कैसा समीकरण बनायेगा?

जापान के गुलदाऊदी सिंहासन पर नये सम्राट ५५ वर्षीय अकीहितो आसीन हुए है। हालांकि दिवंगत सम्राट हिरोहितो ने १९४५ में ही धरती पर ईश्वर का अवतार होने की उपाधि का त्याग कर दिया था, पर जापान में अब दिवंगत सम्राट की अंत्येष्टि और साल भर बाद नये सम्राट की गद्दीनशीनी के लिए जो तैयारी हो रही है, उसको लेकर तरह-तरह की चर्चा चल पड़ी है। इसी २४ फरवरी को होनेवाली सम्राट हिरोहितो की अंत्येष्टि की सूचना लगभग १६० देशों को भेजी जा चुकी है। सम्राट हिरोहितो ने द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानी सेना के कार्यों का समूचा दोष स्वयं ओढ़ लिया था। पश्चिमी देश और उनके मित्र द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेना द्वारा किये गये अत्याचारों को आज भी नहीं भूले हैं। इन देशों में ऐसे हजारों व्यक्ति जिंदा हैं, जिन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया था और युद्धबंदी की हैसियत से भारी यातनाएं झेली थीं। ४० वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वे जापान को क्षमा करने को तैयार नही हैं। ऐसे कई देश हो सकते हैं, जो अपने पूर्व सैनिकों की भावनाओं का आदर करते हुए सम्राट हिरोहितो की अंत्येष्टि से दूर रहना चाहेंगे। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बाब हाक ने तो कह दिया है, "मैं हिरोहितो की अंत्येष्टि में भाग लेने नहीं जाऊंगा।" ब्रिटेन की महारानी जापान हो आयी हैं। जापान के साथ ब्रिटेन समेत सभी पश्चिमी देशों के बहुत अच्छे संबंध हैं। युवराज की हैसियत से अकीहितो ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों का दौरा कर चुके हैं। सम्राट अकीहितो के दोनों पुत्र राजकुमार नारूहितो (हिरो) और राजकुमार अया आक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। पर सम्राट हिरोहितो की अंत्येष्टि में भाग लेने ब्रिटेन की महारानी टोक्यो नहीं जा रही हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति एडिनबरा के ड्यूक जापान जायेंगे। ब्रितानी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सर ज्योफ्री हाव ड्यूक के साथ टोक्यो जायेंगे। ड्यूक द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रितानी सेना में थे और जापान के विरुद्ध सुदूर पूर्व के मोर्चे पर लड़े थे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस युद्ध के दौरान कुल ४ करोड़ ८० लाख व्यक्तियों ने प्राण गंवाये थे। आमतौर पर कहा जाता है कि जापान, एशिया और प्रशांत क्षेत्र मे इतने व्यक्तियों की मौत का बोझ सम्राट हिरोहितो के सिर पर था।

पश्चिम का रवैया: सम्राट हिरोहितो के प्रति पश्चिम का रवैया कभी अनुकूल नहीं रहा। कहा जाता है कि युद्ध खतम होने के बाद जनरल मैकआर्थर और राष्ट्रपति ट्रूमन के बीच मतभेद पैदा हो गये थे। इस विवाद में मैकआर्थर को जापान के सम्राट के सहयोग की अपेक्षा थी। सिंहासन बचाने के लिए हिरोहितो मैकआर्थर का सहयोग चाहते थे। सो दोनों में एका कायम हुआ और गुलदाऊदी सिंहासन सुरक्षित रहा। अक्तूबर '८८ में जब सम्राट का स्वास्थ्य अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, तब ब्रिटेन के दो लोकप्रिय टेबलायड समाचार पत्रों 'द सन' और 'द डेली स्टार' ने अपने मुख पृष्ठ पर छापा था "इस शैतान सम्राट की नर्क में प्रतीक्षा हो रही है।" इस प्रसंग में इन पत्रों में जो लेख प्रकाशित हुए उनमें एशिया में जापान के सैनिकों के अत्याचारों की भयावह कहानियां छापी गयी थीं। जापान सरकार ने इस पर अपनी नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि आलेख में जापान के विरुद्ध गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है। न्यूजीलैंड के विदेशमंत्री बाब तिजर्ड ने भी सम्राट हिरोहितो के निधन पर कहा, "युद्ध के दौरान बंदी बनाये गये मेरे सैकड़ों साथियों और अन्य हजारों व्यक्तियों की हत्या के लिए हिरोहितो दोषी हैं। युद्ध के बाद मुकदमा चला कर या तो उन्हें गोली मारी जानी चाहिए थी या फिर कुल्हाड़े से उनका सिर काटा जाता।" ब्रितानी पत्रों में छपी कहानी या तिजर्ड का बयान इसका पहला संकेत है कि जापान में जो युग समांप्त हो रहा है उसके बारे में दुनिया के एक बड़े भाग से आनेवाली ये कर्णकटु बोलियां सुनने को उसे तैयार रहना चाहिए। सम्राट हिरोहितो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री तकेशता ने कहा कि सम्राट युद्ध के विरुद्ध थे और उनके संकल्प से ही शांति लौटी थी। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि तकेशता को कुछ मालूम नहीं कि वे क्या बोल रहे हैं।

ऐसा जान पड़ता है कि सम्राट हिरोहितो जाते-जाते जापान को उस दोराहे पर छोड़ गये हैं, जहां उसे साहस और आत्मविश्वास का परिचय देना होगा। हिरोहितो ने कहा था कि जब व्यक्ति या राष्ट्र के जीवन में निर्णय की घड़ी आती है, तब उसका साहस और संकल्प ही काम आता है।

जापान के भीतर भी सम्राट हिरोहितो की युद्धकालीन भूमिका को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सम्राट हिरोहितो की मृत्यु के बाद युवराज अकीहितो को सम्राट घोषित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में जापान के सभी मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि उपस्थित थे, पर जापानी संसद की लोकसभा और प्रतिनिधिसभा के समाजवादी और कम्युनिस्ट सदस्य अनुपस्थित रहे। जापान की कम्युनिस्ट पार्टी अर्से से मांग करती आ रही है कि

दर्दनाक याद: जापान के सम्राट (स्व०) हिरोहितो

राजशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। अकीहितो को सम्राट घोषित किये जाने की राय का बहिष्कार करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया कि नये सम्राट को सिंहासन पर बिठाने की परंपरा चलाना संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान सरकार और धर्म को एक दूसरे से अलग रखने की बात कहता है। कम्युनिस्ट पार्टी का यह बयान स्पष्टतः सम्राट अकीहितो की इस घोषणा का जवाब था कि वे जापान के संविधान का परिपालन करने में, जिसकी व्यवस्था के अनुसार सम्राट राज्य का प्रतीक है, जनता के हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। अकीहितो ने सम्राट के रूप में अपनी पहली घोषणा में यह भी कहा था कि वे जापानी संविधान और राजपरिवार के विधान के अनुसार सिंहासनारूढ़ हो रहे हैं, तथा वे अपने पिता दिवंगत सम्राट हिरोहितो के चिह्नों पर चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वे दिवंगत सम्राट की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का संकल्प करते हैं।

कम्युनिस्टों का विरोध : कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध का कारण यह है कि शिंतो धर्म की परंपरा के अनुसार राजा सर्वोच्च धर्मगुरु और पुरोहित भी है। सम्राट हिरोहितो या अब सम्राट अकीहितो को सम्राट घोषित किये जाने का विरोध करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्षमंडल के स्थायी सदस्य ईजो कोबायाशी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "हमें इस सिद्धांत को रेखांकित करना चाहिए कि संप्रभुता जनता में निहित है।" पर जापान की सरकार और विदेश विभाग सम्राट को राज्याध्यक्ष मानते हैं और अन्य देशों से कहते हैं कि वे भी जापान के सम्राट को इसी रूप में स्वीकार करें।

> **अकीहितो को सम्राट घोषित किये जाने की राय का बहिष्कार करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया कि नये सम्राट को सिंहासन पर बिठाने की परंपरा चलाना संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान सरकार और धर्म को एक दूसरे से अलग रखने की बात कहता है।**

दैनिक 'अशाही शिम्बुन' द्वारा करायी गयी एक मतगणना के अनुसार जापान की लगभग ९० प्रतिशत आबादी सम्राट के स्वरूप और स्थिति को बरकरार रखने के पक्ष में हैं, जबकि लगभग १० प्रतिशत का मत है कि लोकतंत्र में सम्राट की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता के सोच में आया यह बदलाव हो सकता है सम्राट हिरोहितो की बीमारी से जागी सहज सहानुभूति का परिणाम रहा हो, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जापानी जनता का भी एक भाग सम्राट और सिंहासन को बनाये रखने के विरुद्ध है। यह विरोध द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सम्राट हिरोहितो की भूमिका से संबद्ध रहा, जिसकी छाया से युद्ध के बाद का उनका कार्यकाल मुक्त नहीं हो सका। जापान की 'क्योदो संवाद समिति' ने १९८४ में इस प्रसंग में जनता की राय जानने की कोशिश की थी। तब २५ प्रतिशत व्यक्तियों ने कहा था कि सम्राट हिरोहितो द्वितीय विश्वयुद्ध के अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। लगभग इतने ही व्यक्तियों ने सम्राट को निर्दोष बताया था, जबकि ४२ प्रतिशत ने कहा था, "हम नहीं जानते।"

आशाही शिम्बुन ने १९८६ में भी जनता से पूछा था कि सम्राट हिरोहितो के प्रति उनकी भावनाएं क्या हैं? ४० प्रतिशत ने कहा था कि हिरोहितो से उनका कोई लगाव नहीं। सिर्फ २२ प्रतिशत जापानियों ने कहा था कि सम्राट को वे अपना मित्र मानते हैं।

जहां तक युवराज अकीहितो की बात है, उन्होंने राजपरिवार की परंपरा से हटकर एक सामान्य परिवार की कन्या से विवाह किया है। उन्होंने सामान्य व्यक्तियों की तरह रहना शुरू किया है तथा राजपरिवार और जनता के बीच की दूरी खतम करके जनता के राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं। पर उनके इस तौर-तरीके पर जापान के एक युवा इतिहासकार मिचीनोरी कोबायाशी ने कहा, "राजपरिवार को आधुनिक आम परिवार जैसा बनाने का प्रयोग खतरनाक है, क्योंकि इससे एक बहुमूल्य संस्था का अवमूल्यन हो जायेगा।" जापान की पत्रिका 'गेनदाई' में गत वर्ष एक लेखक ने मत व्यक्त किया था कि जापान का सम्राट ऐसा हो कि उसे जनता उस रूप में स्वीकार कर सके। जनता क्या चाहती है, इस बारे में आर्थिक आयोजन अभिकरण के एक सर्वेक्षण से पता चला कि दो तिहाई जापानी नहीं चाहते कि जापानी युवक-युवतियां विदेशियों से विवाह करें। एक अन्य सर्वेक्षण से पता चला कि ४५.८ प्रतिशत जापानी विदेशियों से दोस्ती करना पसंद नहीं करते। जापानियों में उभरता यह उग्र राष्ट्रवादी भाव जापान के अनुदार राजनीतिक दलों को अधिक रास आता है। वे इससे लाभ उठाने को भी तैयार रहते हैं। सम्राट हिरोहितो के राज्यारोहण की १९८६ में हीरक जयंती मनाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नकासोने ने चुनाव कराया और भारी बहुमत से जीते थे।

संविधान का सम्मान : युवराज अकीहितो

जापान का शासक दल देश में अनुदारवादी राष्ट्रवाद के उभार का स्वागत इसलिए भी करेगा कि इससे उसे अपनी विश्वव्यापी भूमिका तय करने और अमरीकी प्रभाव से युक्त होने का मौका मिलेगा। दुनिया में सैनिक शक्ति का महत्व घटने और आर्थिक शक्ति की पूजा शुरू होने के बाद यह और जरूरी हो गया है कि जापान अपनी स्वतंत्र भूमिका तय करे।

साहस की परीक्षा : जापान के भीतर और बाहर भी ऐसा समझा जा रहा है कि सम्राट हिरोहितो के जाने और अकीहितो के नये सम्राट बनने से देश के सामने नयी चुनौती और नये अवसर आये हैं। सिंगापुर, फिलिपीन आदि देशों ने अंत्येष्टि में भाग न लेने की बात कही है। अमरीका के राष्ट्रपति बुश अंत्येष्टि में भाग लेने जापान जायेंगे। जापान स्वयं चाहता है कि विदेशों के उच्चस्तरीय मंडल अंत्येष्टि में भाग लेने आयें। यह दिवंगत व्यक्ति के पद और सम्मान के अनुरूप होगा। पर यह भी साफ है कि हिरोहितो के निधन के बाद दुनिया में द्वितीय विश्वयुद्ध की याद ताजा हुई है। हजारों व्यक्तियों के मारे जाने की कहानियां दोहरायी जाने लगी हैं। जापानी जनता को भी अपने अतीत में झांकने का मौका मिला है। हो सकता है, सम्राट हिरोहितो की अंत्येष्टि के प्रति विदेशी रवैये से उसे फिर अपने आपको समझने का मौका मिले। ऐसा जान पड़ता है कि सम्राट हिरोहितो जाते-जाते जापान को उस दोराहे पर छोड़ गये हैं, जहां उसे साहस और आत्मविश्वास का परिचय देना होगा। हिरोहितो ने कहा था कि जब व्यक्ति या राष्ट्र के जीवन में निर्णय की घड़ी आती है, तब उसका साहस और संकल्प ही काम आता है। ऐसे क्षण में यह कहना गलत न होगा कि हिरोहितो की अंत्येष्टि के समय एक बार फिर जापानी साहस की परीक्षा होगी।

—रामपाल सिंह

राष्ट्रीय अभियान समिति

वामपंथी दलों ने क्या खोया, क्या पाया ?

हसी या झेप ? : राष्ट्रीय अभियान समिति के नेताओं के केंद्र में हेमवती नंदन बहुगुणा

राष्ट्रीय मोर्चे और जनता दल में वांछित स्थिति प्राप्त करने में विफल बहुगुणा, रामधन आदि नेताओं और दलों ने 'राष्ट्रीय अभियान समिति' गठित कर अपना भाव बढ़ाने की जो चाल चली, उससे न केवल विपक्ष की मुख्यधारा, बल्कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी बिदकी हुई दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ ? और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होनेवाला है ?

सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, वामपंथी दलों, विशेषकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेताओं को इसका कतई गुमान न था। यदि होता, तो गत ११ जनवरी को अन्य छह दलों—भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), फारवर्ड ब्लाक, आरएसपी, लोकदल-ब, कांग्रेस-स और जनमोर्चा—के साथ राष्ट्रीय अभियान समिति बनाने की घोषणा से पूर्व वे उस पर एक बार नहीं, बल्कि दस बार पुनर्विचार करते। समिति के गठन के उपरांत ही उनको पार्टी के भीतर और बाहर जिस तीव्र प्रतिक्रिया और आलोचना का सामना करना पड़ा है, उसने माकपा को तो सांसत में डाला ही है, स्वयं समिति के अस्तित्व और उसकी सफलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

वर्तमान समस्या का प्रमुख कारण समिति के घोषित उद्देश्य (वामपंथी और लोकतांत्रिक कार्यक्रमों द्वारा जनमत बनाना) का किसी के भी गले न उतरना ही रहा है। समिति के राजनीतिक बयान जारी करते समय सभी दलों के प्रमुख नेताओं (चाहे वे ईएमएस नंबूदिरीपाद हों या हरकिशन सिंह सुरजीत, हेमवती नंदन बहुगुणा, इंद्रजीत गुप्त, एम फारूकी, रामधन, त्रिदिव चौधरी, केपी उन्नीकृष्णन अथवा शास्त्री) की मौजूदगी विशेष महत्वपूर्ण रही। प्रत्येक घटक के समुचित प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त इसने यह भी स्पष्ट दर्शाया कि हर घटक ने इसको कितनी अहमियत दी है। यह दूसरी बात है कि अधिसंख्य अन्य विपक्षी दलों ने इसे 'दबाव की राजनीति का द्योतक' करार दे 'जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे को दिशानिर्देश देने की नीयत से ओतप्रोत' बताया।

दिलचस्प बात यह है कि समिति के आरंभ की घोषणा के दौरान लगभग सभी मौजूद नेताओं-वक्ताओं ने बराबर इस बात पर जोर दिया कि यह मात्र १५ मुद्दों पर अभियान चलाने की समिति थी, तीसरा मोर्चा नहीं। फिर भी अन्य दलों ने समिति के बहाने तीसरा मोर्चा खोलने—चाहे अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो—का आरोप लगाया। राष्ट्रीय मोर्चे के महामंत्री, तेलुगूदेशम सांसद पी उपेंद्र ने 'माया' से कहा, "यदि बात मात्र एक रेडिकल अभियान चलाने की ही थी, तो वामपंथियों को राष्ट्रीय मोर्चे के तहत ऐसा करने से किसने रोका था ? कम से कम राष्ट्रीय मोर्चे को इसका सुझाव और इस पर विचार-विमर्श का मौका तो देते। सच तो यह है कि इस संबंध में न तो हमसे पूछा ही गया और न हमको कोई पूर्व सूचना ही दी गयी। वामपंथियों, विशेषकर भाकपा, को इतना बड़ा कदम उठाने से पूर्व राष्ट्रीय मोर्चे के भीतर इसकी चर्चा अवश्य करनी चाहिए थी।"

जवाब में भाकपा सचिव एम फारूकी बोले, "हम लोग तो शुरू से कांग्रेस का कार्यक्रम-प्रधान विकल्प खोजने की बात करते रहे हैं। किंतु मध्यमार्गी पार्टियां १९७७ का जुनून जगाने और पदों के चक्कर में अधिक रही हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य राजीव का विकेट गिराना रहा है। कार्यक्रमों का आधार बनाना तो दरकिनार, कइयों ने तो हमें यह भी समझाया कि कार्यक्रम और नीति सुनिश्चित करने से विपक्ष में विभाजन का खतरा पैदा हो जायेगा। हमारा कहना था कि यह विभाजन तो फिर सरकार बनाने के बाद भी हो सकता है। इसलिए महज विभाजन और मतभेद के डर से

नीति-निर्धारण न करना उचित नहीं। विशेषकर तब, तब जनता पार्टी, जनता शासन और उसके पतन का उदाहरण हमारे सामने है। मध्यमार्गी पार्टियों के सही रिस्पांस (प्रत्युत्तर) के अभाव में ही हमने स्वयं पहल करने का निश्चय किया।"

कांग्रेस-स के महासचिव केपी उन्नीकृष्णन के अनुसार उनके दल ने जनता दल में न शामिल होने का निर्णय ही इसी कारण लिया था कि वे कार्यक्रम पर आधारित विकल्प प्रस्तुत करने की बात कर रहे थे, जबकि अन्य दल कुरसी की मार-धाड़ को अधिक अहमियत दे रहे थे।

आरोपों-प्रत्यारोपों की पुरजोर बारिश के चलते इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि विपक्ष आज तक अपनी भावी लाइन नहीं तय कर पाया है। जनता दल, कुरसी की लड़ाइयों के चलते यदि किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट रवैया अपनाने से दूर रहा है, तो राष्ट्रीय मोर्चे ने ७१ सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा हर खेमे और विचारधारा को समेटने, प्रसन्न रखने का प्रयास किया है। नतीजे में दोनों को एक ही चीज मिली है—किसी भी प्रकार का आंदोलन, अभियान, मुहिम छेड़ने में नाकामी।

किंतु इसका अर्थ न तो यह है कि वामपंथियों ने महज इसी विपक्षी असफलता के कारण अपना अलग राग अलापा है और न ही यह कि उनके १५ मुद्दे अपने आप में कोई ऐसा अजूबा हैं, जिससे अप्रत्याशित सफलता पांव चूमती दिखायी देगी। सांप्रदायिकता, विघटनवाद की खिलाफत, राष्ट्रीय एकता और एकात्मता, ऊंचे पदों के भ्रष्टाचार और कालेधन की खिलाफत, नागरिक स्वाधीनता और लोकतांत्रिक अधिकार, आर्थिक स्वावलंबन, सार्वजनिक क्षेत्र की तरफदारी और एकाधिकारी घरानों का विरोध, मूल्य वृद्धि के खिलाफ मुहिम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुरुस्ती, काम के अधिकार को मूलाधिकारों में शामिल कराना, खेतिहरों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना, भूमि सुधार कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराना, निरक्षरता की समाप्ति, श्रमविरोधी नीतियों का परदाफाश, वनोपज संसाधनों की सुरक्षा, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संचार-साधन, विश्वशांति, गुट-निरपेक्षता और साम्राज्यवाद-विरोधी विदेश नीति आदि को अभियान समिति के कार्यक्रम में गिनाया गया है। इनमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं जिसे अन्य विपक्षी दल तो दूर, विपरीत ध्रुव पर बैठी वामपंथियों की घोषित दुश्मन भाजपा भी मानने, अभियान चलाने में आनाकानी करे। जाहिर है कि लक्ष्य और कारण कुछ दूसरे ही हैं।

भाजपा ही जिम्मेदार : अधिकांश पर्यवेक्षक भाजपा को ही वामपंथ की वर्तमान नीति और कार्यक्रम का प्रमुख कारण भी मानते हैं और लक्ष्य भी। अभियान समिति के गठन के फौरी कारण के पीछे दो महत्वपूर्ण तथ्य रहे। एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कुछ दिनों पूर्व की गयी यह घोषणा कि जिस प्रकार फुटबाल के मैदान में वे दायें-बायें दोनों से गोल करते थे उसी प्रकार राजनीति के फुटबाल में वे वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों से तालमेल बनायेंगे। यही नहीं, चौधरी देवीलाल ने जोश में यह भी ऐलान कर दिया कि जनता दल ने उन्हें भाजपा से बातचीत का अधिकार सौंप दिया है। जाहिर है, बात माकपा नेताओं के गले आसानी से उतरनेवाली नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो भाजपा सदैव ही कांग्रेस से ज्यादा बड़ी दुश्मन नजर आयी है। दूसरे, १२ जनवरी को देवीलाल की अध्यक्षता में होनेवाले जनता ससदीय बोर्ड की बैठक जिस पर दबाव डालने के लिए एक नये जमघट को आननफानन पेश करना अनिवार्य रहा। उल्लेखनीय है कि अभियान समिति के गठन द्वारा कांग्रेस को हटाने की बात अवश्य की गयी, किंतु राजनीति समूचे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने की ही थी। भाजपा महासचिव कृष्णलाल शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा, "हमें आशंका इस बात की है कि वामपंथी पार्टियां, विशेषकर माकपा, एक बार फिर वैसी ही परिस्थितियां न बना दें जैसी उन्होंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समूचे विपक्ष के बीच अनिर्णय और अनिश्चय फैला कर पैदा कर दी थी।

जब इसकी चर्चा भाकपा के वरिष्ठ नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत से चली तो वे बोले, "राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपनायी गयी भूमिका पर हमें गर्व है। हमने डंके की चोट पर ऐलान किया था कि हम किसी भी ऐसे कदम और साजिश में नहीं शामिल होंगे जिससे हमारे संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा पर आंच आये। अन्य दलों का प्रधानमंत्री की बरखास्तगी वाला सुझाव न केवल असंवैधानिक था, बल्कि राष्ट्रीय हित के विपरीत भी। भाजपा जो खेल खेल रही थी, उसने हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का ही खात्मा कर दिया होता।"

जहां तक अन्य दलों का संबंध है, जबतक वे भाजपा से दूर रहे तबतक भाकपा चैन की बंसी बजाती रही। उनकी वर्तमान चिंता और हैरानी तब बढ़ी जब अन्य दल तो दूर, कल तक वामपंथ को अपना 'स्वाभाविक सहयोगी' करार देनेवाले जनता दल अध्यक्ष और राष्ट्रीय मोर्चे के संयोजक विश्वनाथ प्रताप सिंह भी भाजपा से तालमेल बिठाने को उत्सुक दिखायी देने लगे। जनता दल और वीपी सिंह के वर्तमान रवैये पर प्रकाश डालते हुए बहुचर्चित नेता शरद यादव ने 'माया' को बताया, "हम न तो इतिहास बदल सकते हैं और न ही भूगोल। न तो हम यह भूल सकते हैं कि '७७ में जनसंघ (वर्तमान भाजपा) हमारे साथ था, न ही इस तथ्य को अनदेखा कर सकते हैं कि कई स्थानों पर भाजपा का अपना प्रभाव है। पहले '६७ फिर '७७ में वामपंथ ने जनसंघ के साथ मिलकर या तो सरकार बनायी थी अथवा उन्हें अपना सहयोग-समर्थन दिया था। अतः आज बदला रवैया क्यों ?"

बहुगुणा का जाल : जानकार सूत्र इस बदले रवैये और अभियान समिति की आड़ में पुराने मित्रों, विशेषकर बहुगुणा, को सहायता-सहयोग, समर्थन-सुरक्षा देना ही उद्देश्य बताते हैं, तो कुछ अन्य 'बहुगुणा के फेंके जाल में' वामपंथ के फंस जाने की बात करते हैं। ज्ञात रहे कि उन्नीकृष्णन से तो भाकपा के प्रगाढ़ और पुराने संबंध हैं ही, स्वयं बहुगुणा से उनके गहरे संबंध भी लुके-छिपे नहीं हैं। बहुगुणा का वामपंथी रुझान और सोवियत संघ से उनके संबंध भी जाने-पहचाने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुगुणा और भाकपा महासचिव ईएमएस नंबूदिरीपाद में गहरी मित्रता और आपसदारी है। यहां तक कि पिछले वर्ष जब 'सजद' (समाजवादी जनता दल) के गठन की बातचीत चल रही थी, भाकपा के पोलित ब्यूरो के समस्त सदस्यों को रात्रिभोज पर बुला उनसे विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि की भेंट कराने में बहुगुणा आगे रहे थे। सजद तो बना नहीं, जनता दल में भी जगह पाने से बहुगुणा वंचित रह गये। बनते-बदलते समीकरणों से हालात हाशिये पर चले जानेवाले बन गये। इसी से उबरने-उबारने के लिए जरूरत एक अदद समर्थ शरणस्थली

भविष्य साफ नहीं : अभियान समिति की घोषणा के समय इंद्रजीत गुप्त और रामधन

और संगठन की थी, जो अंततोगत्वा अभियान समिति के रूप में या तो हासिल हो गयी या कर ली गयी।

शरणस्थली की दरकार अकेले बहुगुणा को ही नहीं थी। उसकी खोज और आवश्यकता जनमोर्चा संयोजक रामधन को भी थी और उन्नीकृष्णन को भी। हां, कारण अवश्य भिन्न थे। किंतु जनता दल से छूटने अथवा अलग रहने का एक समान कारण भी था, जो तीनों को बांध सकने में सफल रहा। विपक्षी एकता और जनता दल के गठन में विडंबना यह रही कि उसमें शामिल होनेवाले तीनों घटकों-जनता पार्टी, लोकदल-ब व जनमोर्चा—में विघटन पहले हुआ। कांग्रेस-स अंतिम क्षणों में पीछे हट गयी। जनता दल के बढ़ते प्रभाव और फैलते दबाव के चलते लगभग सभी का हाशिये पर चले जाना अपरिहार्य था। जरूरत कम्युनिस्टों को भी कुछ कम न थी। सांगठनिक बल के अतिरिक्त गैर-कम्युनिस्टों द्वारा अपने विचार और हितलाभ फैलाने-बढ़ाने का इससे अच्छा मौका, माहौल और हथियार फिलहाल और क्या हो सकता था? अतः एक छतरी तले आना सभी के लिए लाजमी था।

प्राप्त सूचनाओं और बहुगुणा द्वारा अभियान समिति के गठन की घोषणा के सम्मेलन में अदा की जानेवाली भूमिका ने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया कि पहल के पीछे उनका विशेष हाथ था। साथ ही, यह भी कि अगुवाई भी वही करनेवाले थे। कहा जाता है कि भाकपा महासचिव नंबूदिरीपाद और पोलित ब्यूरो सदस्य हरकिशन सिंह सुरजीत ने समिति के गठन के लिए बहुगुणा की भरपूर हौसला-अफजाई की। पहले केवल भाकपा को इससे अवगत कराया गया। बाद में इसका क्षेत्र अधिक व्यापक बनाने के लिए फारवर्ड ब्लाक और आरएसपी को शामिल किया गया। यद्यपि दोनों की दृष्टि में बहुगुणा संदिग्ध थे, किंतु भाकपा के साथ केरल, बंगाल में वाम मोर्चा सरकारें चलानेवालों के लिए आग्रह टालना संभव न था। स्वयं उन्नीकृष्णन के अनुसार पहल बहुगुणा ने की थी और चूंकि हम स्वयं कार्यक्रम प्रधान विकल्प बनाने की बात सोच रहे थे, सो बहुगुणा के सुझाव को समझने-मानने में कोई समस्या न रही।

सहमति और १५ सूत्रीय अभियान कार्यक्रम बनाने के लिए अनेक बैठकें हुईं। कभी एक के घर, कभी दूसरे के ठिकाने पर। इनमें उन्नीकृष्णन के अनुसार किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद नहीं रहा। कांग्रेस का विकल्प ढूंढ़ने का लक्ष्य भी स्पष्ट था और कार्यक्रमों के अभियान का साधन भी। चूंकि मकसद चुनावी न था और अन्य दलों में कुरसी के लिए घमासान का उदाहरण सामने था, इसलिए समिति को किसी प्रकार की संस्थागत शक्ल नहीं दी गयी। उन्नीकृष्णन का दावा है कि यद्यपि अभियान भावी चुनावों को प्रभावित कर सकता है, किंतु यह हरएक को स्पष्ट रहा कि समिति चुनावी मोर्चा नहीं थी। समिति के गठन की घोषणा के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतें इसमें शामिल हो सकती हैं।

जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे से बातचीत के पहले वामपंथ को बहुगुणा और रामधन से नाता तोड़ना होगा।

ज्योति बसु

उन्नीकृष्णन व उनके साथियों ने भले ही समिति को तीसरे मोर्चे के रूप में अस्वीकारा, किंतु अधिसंख्य अन्य दलों विशेषकर जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे ने इसे इसी रूप में देखा। राजनीतिज्ञों और पर्यवेक्षकों को इसके पीछे वामपंथी और गैर-वामपंथी विपक्ष के मध्य विभाजन द्वारा कांग्रेस को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की नीयत और सोवियत संघ, चीन का हाथ भी दिखायी दिया। विशेषकर इसलिए कि समिति का ऐलान प्रधानमंत्री की बहुचर्चित, बहुप्रचारित चीन-यात्रा के शीघ्र बाद ही हुआ था। आग में घी का काम किया कांग्रेस पार्टी महासचिव केदारनाथ सिंह के समिति के स्वागत, बयान ने। आरोप से सुरजीत विचलित हो गये। बोले "कांग्रेस की मदद का प्रश्न ही कहां है? तिरुअनंतपुरम में हुई अपनी हाल की पार्टी कांग्रेस में हमने जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे के गठन का स्वागत भी किया है। हम न तो किसी बाहरी शक्ति से राय-सलाह मांगते ही हैं और न ही कोई हमें दिशानिर्देश देता है। रही केएन सिंह की बात, तो हमने तो उनके बयान के तुरंत बाद उनसे खुली अपील की है कि यदि वे वास्तव में चिंतित हैं, तो उन्हें हमारे साथ आकर कांग्रेस का विरोध आरंभ करना चाहिए।"

इस संदर्भ में जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे में प्रतिक्रिया तुरंत और तीखी होना अपरिहार्य था। दोनों ने इसको दबाव की राजनीति का हिस्सा तो बताया ही, इसके तहत मुद्दों पर मजबूर करने के अतिरिक्त बहुगुणा, रामधन आदि को राष्ट्रीय मोर्चे में पिछले दरवाजे से प्रवेश दिलाने की चेष्टा का आरोप भी लगाया। जवाबी हमले में रामाराव ने तो बहुगुणा और रामधन गुटों को राष्ट्रीय मोर्चे का सदस्य तक मानने से इनकार कर दिया। वीपी सिंह तो एक कदम और आगे बढ़ गये। ऐलान किया कि राष्ट्रीय मोर्चे और जनता दल से बातचीत के पहले वामपंथ को बहुगुणा-रामधन गुटों से संबंध-विच्छेद करना होगा।

कहीं माकपा ने हाथ खींचा, तो अभियान समिति की भ्रूणहत्या की संभावना बढ़ जायेगी।

उन्नीकृष्णन

इस पूर्णतया अनपेक्षित प्रतिक्रिया से बाजी पलट गयी थी। तीनों प्रमुख मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के स्थान पर वीपी सिंह ने उनमें और बहुगुणा-रामधन में चयन करने की खुली चुनौती पेश कर दी थी। अतः समस्त खेमों में हड़कंप लाजिमी रहा। सुरजीत ने वीपी सिंह, अजीत सिंह आदि जनता दल नेताओं से मिल सुलह-सफाई करनी चाही, पर वहां रवैया सख्त ही रहा।

मजबूत विकल्प की चाह: सुरजीत अभी भी यही कह रहे हैं कि अभियान समिति अपने पुराने कार्यक्रम पर मुहिम चलायेगी। उनके अनुसार देर-सवेर चाहे कितनी ही क्यों न हो, किंतु मध्यमार्गी दलों को अंततः यह स्वीकार करना होगा कि वामपंथी झुकाव के बिना कांग्रेस का विकल्प ढूंढ़ना या बना पाना असंभव है। जनता दल राष्ट्रीय मोर्चे की प्रतिक्रिया को वे दोनों जगह चल रहे गृहयुद्ध का ही एक अंग मानते हैं। राष्ट्रीय मोर्चे से बहुगुणा और रामधन के निष्कासन को गलत करार देते हुए सुरजीत बोले, "राष्ट्रीय मोर्चे में वे क्यों नही रह सकते? वह तो कोई एकीकृत दल नहीं?" जवाब दिया पी उपेंद्र ने, "राष्ट्रीय मोर्चा विपक्षी एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से बना है। इसमें असंतुष्ट गुटों को मान्यता देकर हम शामिल दलों की गिनती नहीं बढ़ा सकते। रही नियम-कानून की बात जो रामधन-बहुगुणा कर रहे हैं, तो यह एक स्वयंसेवी संगठन है, कोई दल नहीं जहां संविधान की दुहाई देकर लोग जबर्दस्ती बने रहें।

हाल की दो घटनाओं के राष्ट्रीय अभियान समिति पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। पहली, राष्ट्रीय मोर्चे के सदस्य दल द्रमुक की तमिलनाडु चुनाव में अभूतपूर्व विजय। राष्ट्रीय मोर्चे के झंडे तले लड़े इस प्रथम चुनाव में मिली यह विजय निश्चय ही मोर्चे की मोल-तोल की हैसियत में इजाफा करेगी। दूसरे, गत २४ जनवरी को ज्योति बसु के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह की भेंट। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दोनों में अभियान समिति और भावी तालमेल के संदर्भ में एक समझदारी बन गयी है।

बदले संदर्भ में यदि माकपा अभियान समिति को भरपूर समर्थन देने में असमर्थ रहे, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में अभियान समिति का क्या भविष्य होगा? जाहिर है, यदि ऐसा हुआ तो अभियान समिति की सफलता तो संदिग्ध होगी ही, उसकी भ्रूणहत्या की संभावना भी बढ़ जाती है। वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करते हुए शरद यादव बोले, "मुझे अफसोस है कि कम्युनिस्टों जैसी बड़ी पार्टी ने छुटे, चुके, ठुके और रुके हुए लोगों की जमात से नाता जोड़ा है जिसका कोई अच्छा नतीजा निकलने वाला नहीं।" यदि कम्युनिस्ट भी आज यही सोच जल्दबाजी में उठाये इस कदम के लिए मन-ही-मन अपने को धिक्कार रहे हों, तो कोई आश्चर्य न होगा।

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

—रंजना कक्कड़

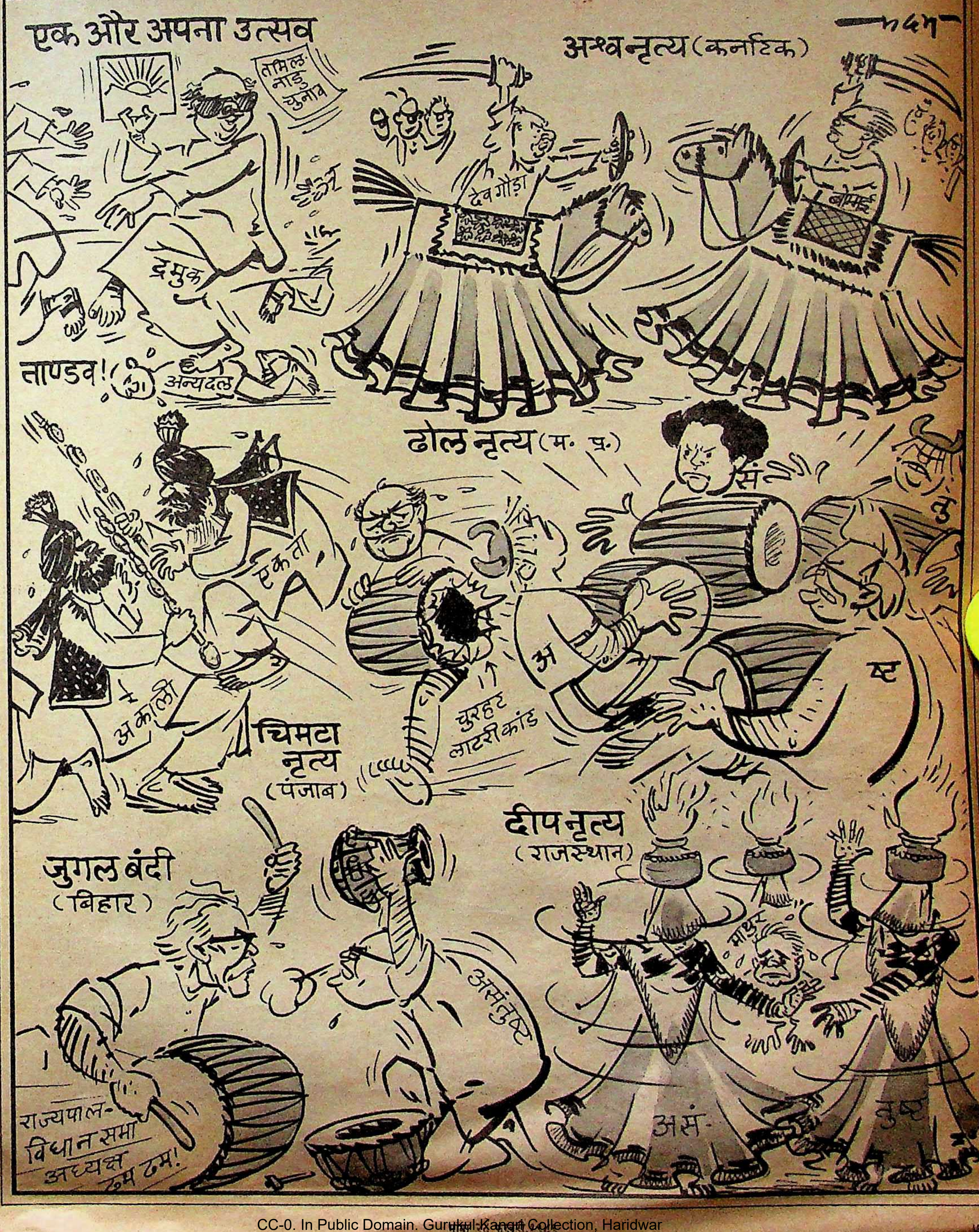
एक और अपना उत्सव
तमिल नाडु चुनाव
द्रमुक
ताण्डव!
अन्य दल
अश्व नृत्य (कर्नाटक)
देवगौड़ा
बोम्मई
ढोल नृत्य (म॰ प्र॰)
सं
एकता
अकाली
चिमटा नृत्य (पंजाब)
चुरहट लाटरी कांड
अ
स
दीप नृत्य (राजस्थान)
माथुर
जुगल बंदी (बिहार)
असंतुष्ट
राज्यपाल-विधान सभा अध्यक्ष
ढम ढम!
असं
तुष्ट

कनाडावासियों का दृढ़ विश्वास
MOODS
SKIN-THIN
LUBRICATED
3 CONDOMS
COLOURED

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम)
विश्व में सर्वाधिक कोण्डोम विनिर्माता

कौन कहता है कि केवल भारतीय
विदेशी मालों पर लट्टू हैं ?

अब कनाडावासी भी आयातित ब्रांड माँग रहे हैं ।
जैसा कि भारत में विनिर्मित कोण्डोम्स ।

फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि कनाडावासी के लिए
वह लट्टूपन नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास है ।

क्योंकि वे जानते हैं कि मूड्स कोण्डोम
जापान के ओकोमोटो के तकनीकी सहयोग से
विश्व में सर्वाधिक कोण्डोम विनिर्माता से
सर्वोत्कृष्ट गुणवाले लेटेक्स से बनाये जाते हैं ।

और मूड्स विश्व में अत्यन्त पतले कोण्डोमों
में गिना जाता है; उसका एहसास १००% स्वाभाविक है ।

साथ ही, ऐड्स आदि लिंग द्वारा प्रसारित
बीमारियों से अधिक संरक्षण प्रदान करता है ।

कनाडा को, लाखों मूड्स का निर्यात किया जा रहा है ।
मोज़ाम्बिक को भी लाखों मूड्स भेजे जा चुके हैं,
यद्यपि इन देशों में संसार-भर के प्रायः सभी ब्रांडों
के कोण्डोम आसानी से मिल जाते हैं ।

और क्या आपको अब भी आयातित कोण्डोम
जिनकी गुणवत्ता संदेहास्पद है, माँगने में कोई झिझक नहीं होती ?

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय कोण्डोम नाम से माँगे ।
मूड्स को नाम से माँगे ।

आत्मविश्वास के साथ चलें
मूड्स को माँगे–
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के
भारतीय कोण्डोम

R K SWAMY/HLL/6662/HIN

प्रेम नजीर

मलयालम सिनेमा के पर्याय माने जाने वाले मशहूर अभिनेता प्रेम नजीर १६ जनवरी को नही रहे। प्रेम नजीर को खूनी अल्सर की शिकायत के बाद विगत २६ दिसंबर को मद्रास के एक चिकित्सालय में भरती कराया गया था, लेकिन डाक्टरों के हर संभव प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।

२६ दिसंबर, १९२९ में तिरुअनंतपुरम जिले के चिरयांकिल नामक गांव में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे प्रेम नजीर का बचपन का नाम अब्दुल कादिर था। प्रेम नजीर को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी। रंगमंच से जीवन की शुरुआत करने वाले प्रेम नजीर की पहली मलयालम फिल्म 'मारुमकाल' (पुत्रबधू) १९५१ में बनी। इसके बाद वे एक के बाद एक फिल्में करते गये। अपने ग्लैमरस रूप-रंग और रोमानी अंदाज के चलते वे इतने लोकप्रिय हो गये कि केरल के घर-घर में छा गये। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जानी-मानी अभिनेत्री शीला के साथ ११० तथा जयाभारती के साथ ५० फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। यों तो उन्होंने लगभग ८६ नायिकाओं के साथ ७०० फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी 'इरुत्तिते आत्माउ', 'आदिमकाल', 'असुराविथु', 'नागमथे नदी', और 'मुराप्पेन्नु' आदि सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती हैं। उन्होंने मलयालम के अलावा तमिल (५५ फिल्म), तेलुगू और कन्नड़ भाषाओं की अनेक फिल्मों में काम किया। सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए १९८३ में उन्हें 'पद्मभूषण' से तो अलंकृत किया ही गया, केरल सरकार ने भी उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सबसे अधिक फिल्मों में काम करने के लिए दर्ज है।

विश्व फिल्म इतिहास में कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्रेम नजीर जितने बड़े कलाकार थे, उतने ही बड़े इंसान भी थे। उन्होंने कितनी ही संस्थाओं की आर्थिक सहायता की। अपने गृह-गांव चिरयांकिल में उन्होंने एक स्कूल, एक अस्पताल, एक मस्जिद और एक गिरजाघर भी बनवाया। एनटी रामाराव और एमजी रामचंद्रन की तरह उनकी रुचि राजनीति में भी थी। वे काफी दिनों से एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन उनका जब वह सपना पूरा नहीं हुआ, तो वे कांग्रेस पार्टी (इ) में शामिल हो गये। इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई। १९८९ में वे एक फिल्म के निर्माण की सोच रहे थे, जिसके लिए एक अच्छी कहानी की तलाश में भी थे। इसके लिए उन्होंने कई कहानीकारों से बात भी कर ली थी। मलयालम में उनकी एक टीवी सीरियल बनाने की भी योजना थी। लेकिन निर्माता बनने की उनकी साध पूरी न हो सकी। उनके निधन से मलयालम सिनेमा ही नहीं भारतीय सिनेमा का महत्वपूर्ण पाया टूट गया। ■

अपने ग्लैमरस रूप-रंग और रोमानी अंदाज के चलते वे इतने लोकप्रिय हो गये कि केरल के घर-घर में छा गये।

श्याम नारायण पांडेय

पराधीन भारत में जन-जन में राष्ट्रीयता का उद्घोष करनेवाले महाकवि श्याम नारायण पांडेय का जनवरी की २६वीं तारीख को निधन हो गया। पांडेयजी काफी अरसे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे।

आधुनिक हिंदी काव्य के भूषण कहे जाने वाले श्याम नारायण पांडेय का जन्म आजमगढ़ जिले के डुमरांव नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में १९०७ में हुआ था। उनके पिता पं० रामाज्ञा पांडेय संस्कृत के बड़े धुरंधर विद्वान थे, इसलिए बालक श्याम नारायण पर उनका काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन बचपन में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। पांडेयजी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई, फिर संस्कृत की परंपरागत शिक्षा अर्जित करने के लिए उन्हें काशी भेज दिया गया। काशी के राजकीय संस्कृत विद्यालय से ही उन्होंने शास्त्री और साहित्याचार्य की उपाधियां प्राप्त कीं।

पांडेयजी बचपन से ही साहित्यिक मिजाज के थे। उन्होंने अपने बचपने में ही कई कहानियां संस्कृत में लिखीं, लेकिन उनकी असली प्रतिभा का प्रस्फुटन तो वीर रस में लिखी गयी हिंदी कविताओं में हुआ। १९३७ में उन्होंने 'हल्दी घाटी' नामक महाकाव्य का श्रीगणेश किया। उसके बाद उनकी 'जौहर', 'तुमुल', 'रूपांतर', 'आरती', 'जयहनुमान' आदि काव्यकृतियां प्रकाशित हुईं। लगभग दो दशकों से अधिक समय तक वे कवि सम्मेलनों में अत्यंत लोकप्रिय एवं समादृत रहे। पांडेयजी की विभिन्न रचनाओं पर 'देव' तथा 'द्विवेदी पुरस्कार' जैसे कई साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए।

राष्ट्रीय पुनर्जागरण के काल में बंकिमचंद्र चटर्जी की रचनाओं का जो प्रभाव जनमानस पर पड़ा, उससे कम प्रभाव पांडेयजी की रचनाओं का नहीं पड़ा। फलस्वरूप स्वतंत्रता-संघर्ष के दिनों में 'हल्दी घाटी' का पारायण कर नवयुवकों में जो त्याग-उत्सर्ग और राष्ट्रप्रेम की धारा प्रवाहित हुई, वह खड़ी बोली के किसी अन्य कवि के काव्य द्वारा संभव न हो सकी। उनके देहावसान से निःसंदेह ही हिंदी जगत की अपूरणीय क्षति हुई है।

—डा० मुश्ताक अली

Corner to Corner
Luxury
VOLUME
CHANNEL
POWER
FS BLACKTINT 212 R

VIDEOCON redefines picture clarity.

The 212 R from VIDEOCON incorporates the world famous Tinted FST (picture tube). The flat surface of the screen not only eliminates distortion, but also leaves the corners of the picture "uncropped" allowing you to enjoy the picture from corner to corner – literally.

The Tinted FST (Full Square Picture Tube) also boosts the contrast ratio by 30% to give you high contrast, finely detailed and realistic picture. Being a 53 cm FST colour TV; the viewing angle increases by 20% which means that more people can enjoy the larger, sharper and clearer picture.

The 212 R is also blessed with a host of advanced features like off-timer and Automatic Brightness/contrast Limiter. If you're under the impression that this world class colour TV costs the earth, there's a pleasant surprise awaiting you at your nearest VIDEOCON dealer.

VIDEOCON FST SCREEN

CONVENTIONAL SCREEN

Special Features

■ FST ■ Big Clean and clear picture ■ Remote control ■ On-screen-display ■ Off timer ■ Automatic Voltage Regulator (AVR) ■ Channel Up/Down control ■ Volume Up/Down control ■ Auto search tuning

212 R **53 cm. Colour TV.**

VIDEOCON

SJAS 88133

जीतेंद्र

बंबई का स्टार, दक्षिण का सुपर स्टार

लगभग तीन दशक पहले निर्माता-निर्देशक व्ही शांताराम राजकमल स्टूडियो में 'स्त्री' के सेट पर जब शूटिंग कर रहे थे, तो कैमरे के लेंस से झांकते हुए उनकी निगाह कैमरे के फोकस के बाहर खड़े एक युवक पर ठहर गयी। कुछ देर तक वे उसे उसी लेंस के सहारे देखते रहे, पास खड़े अपने सहायक को कुछ निर्देश दिया और फिर शूटिंग में व्यस्त हो गये। लंच के बाद जब वे सेट पर पहुंचे, तो मेकअप किये वही युवक उनके सहायक के साथ खड़ा एक संवाद का बार-बार रिहर्सल कर रहा था जैसे कोई बला अचानक उसके गले मढ़ दी गयी हो।

व्ही शांताराम बतलाते हैं, "उसमें स्टार क्वालिटीज थीं, ऐक्टिंग टेलेंट माइनस था, लेकिन हमने सोचा कि यह बात रिहर्सलों-आब्जर्वेशन मेथड तथा प्रशिक्षण के जरिये उसमें लायी जा सकती है। उसके चाचा शूटिंग के लिए ज्वेलरी सप्लाई किया करते थे। मैंने उस लड़के को बुलाकर कहा कि बरखुरदार, इस नकली ज्वेलरी-वेलरी में कुछ नहीं रखा है। मेहनत करो, तो बढ़िया ऐक्टर बन सकते हो, नहीं तो स्टार तो बन ही जाओगे।"

व्ही शांताराम ने रवि कपूर नामक उस युवक का नाम जीतेंद्र रख 'गीत गाया पत्थरों ने' में अपनी बेटी राजश्री के साथ हीरो बनाकर फिल्म इंडस्ट्री में दो नये सितारे पेश कर दिये। उसके बाद से जीतेंद्र तीन दशक की लंबी अभिनय-यात्रा में आज स्टार और ऐक्टर के बीच त्रिशंकु-सा बना हुआ है।

फिल्म बाजार के इतिहास में जीतेंद्र बाक्स फार्मूला चमत्कार का प्रतीक है। एक जाने-माने फिल्म वितरक के अनुसार, "अमिताभ बच्चन को लेकर बनी फिल्म की लागत २ करोड़ रुपए पड़ती है, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना आदि सितारों की फिल्म एक करोड़ या ऊपर पड़ती है। इनके बनने में आम तौर पर डेढ़ से ढाई वर्ष का समय लग जाता है, जबकि जीतेंद्र की फिल्में ६०-७५ लाख रुपए से ज्यादा में नहीं पड़तीं और साल भर के अंदर बनकर प्रदर्शित हो जाती हैं।

मोल्डेड आर्टिस्ट: विश्व के फिल्म इतिहास में जीतेंद्र की गणना उन गिने-चुने सुपरस्टारों में की जाती है जिनकी अधिकांश फिल्में बाक्स आफिस पर बुरी तरह से पिटने के बावजूद उनके मार्केट-रेट में निरंतर बढ़ोतरी ही होती है और उन्हें स्टारडम से कोई नही डिगा पाता। प्रख्यात निर्माता-निर्देशक के राघवेंद्र राव ने 'माया' को बतलाया, "जीतेंद्र एक 'मोल्डेड आर्टिस्ट' है, उसे आप जैसा चाहिए, मोड़ दीजिए। वह कभी भी उज्र नहीं करेगा।"

इसकी चर्चा चलने पर जीतेंद्र कहते हैं, "मैं अपने आपको 'डायरेक्टर्स मैन' मानता हूं। पूरी फिल्म का सिनेरियो उसके दिमाग में होता है, पूरी प्लानिंग उसकी होती है। अगर आप उस प्लानिंग की दीवार में अपनी रायों-दखलंदाजियों के ईंट चस्पा करते रहेंगे, तो क्या हाल होगा उस इमारत का? मैं जब सेट पर पहुंचता हूं, तो सिर्फ कलाकार जीतेंद्र होता हूं।"

जीतेन्द्र में ऐसी कौन-सी खासियत है कि वे बाक्स आफिस के गणितज्ञ माने जा रहे हैं?

संघर्ष और स्टारडम: १९६४ में जीतेंद्र की जब पहली फिल्म 'गीत गाया पत्थरों ने' प्रदर्शित हुई थी, तब उसे उस जमाने के तितरफे स्टारडम का सामना करना पड़ा था। उसके एक तरफ थे अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद, गुरुदत्त सरीखे मंजे हुए कलाकार, तो दूसरी तरफ थे राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, प्रदीप कुमार, सुनील दत्त, भारत भूषण जैसे सुपरस्टार, तो तीसरी तरफ थे नये-नये कदमबोसी कर स्टार बन जानेवाले शशि कपूर, विश्वजीत, धर्मेंद्र, मनोज कुमार आदि।

व्ही शांताराम कभी भी अपने कलाकारों को 'रिपीट' नहीं करते थे—लेकिन उन्होने जीतेंद्र को 'रिपीट' किया फिल्म 'बूंद जो बन गयी मोती' से। इसके बाद मद्रास के फिल्मकार एलवी प्रसाद ने जीतेंद्र को लेकर 'जीने की राह' बनायी तथा रवि नगाइच ने उसे पुनः 'जिगरी दोस्त' में रिपीट किया।

१९६४ में फिल्मों मे कदमबोसी के तीन वर्ष बाद १९६७ जीतेंद्र के लिए 'कामयाबी' का तोहफा लेकर आया, जब 'फर्ज' व 'बूंद जो बन गयी मोती' के साथ-साथ 'गुनाहों का देवता', 'परिवार', 'पत्थर के सनम' प्रदर्शित हुईं। जीतेंद्र की कामयाबी ने उसे १९६८-६९ ('मेरे हुजूर', 'अनमोल मोती', 'औलाद', 'सुहागरात', 'धरती कहे पुकार के', 'बड़ी दीदी', 'दो भाई', 'जीने की राह', 'जिगरी दोस्त', 'वारिस') में स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया था और वह फिल्म इंडस्ट्री का सफलतम व सेलेबुल स्टारों में गिना जाने लगा। १९७० में

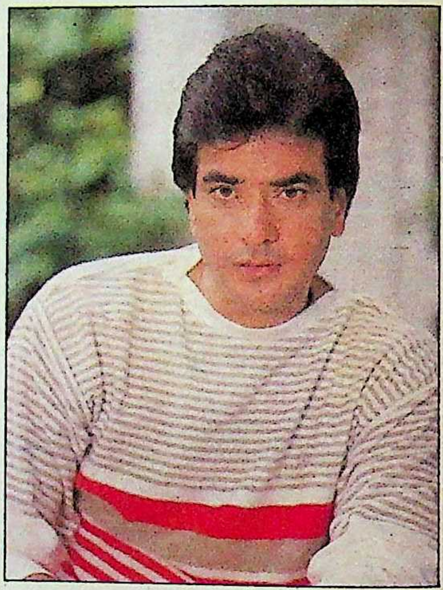

कला पर उम्र का कोई असर नहीं: जीतेन्द्र

दृश्य की मांग के अनुसार अभिनय: जीतेन्द्र और जयाप्रदा

प्रदर्शित 'हिम्मत', 'हमजोली', 'नया रास्ता' तथा 'जवाब' की व्यावसायिक सफलता ने जहां उसके स्टारडम को बरकरार रखा, वहीं राजेश खन्ना के अचानक सुपरस्टार बन जाने की घटना ने जीतेंद्र की पकड़ को ढीली भी कर दी।

राजेश खन्ना ने जहां एक तरफ-पूर्व-नियोजित योजना के तहत दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार से लेकर शम्मी कपूर, विश्वजीत जैसे स्टारों के गढ़ों को ध्वस्त कर उनके 'परमानेंट' प्रोड्यूसरों की फिल्में हथियानी शुरू कर दीं, वहीं जीतेंद्र ने आंख मूंदकर फिल्में लेनी शुरू कीं, फलतः उसके पास सेकेंड ग्रेड फिल्मों का जखीरा लगने लगा, जिसका परिणाम भी उसे तुरंत भुगतना पड़ा। १९७१ में 'बनफूल', 'बलिदान', 'चाहत', 'एक नारी एक ब्रह्मचारी','कठपुतली', 'यार मेरा', 'एक बेचारा', १९७२ में 'एक हसीना दो दीवाने', 'भाई हो तो ऐसा', 'रूप तेरा मस्ताना', 'शादी के बाद' तथा १९७३ में 'अनोखी अदा', 'गहरी चाल', 'जैसे को तैसा' आदि घटिया स्तर की सुपरफ्लाप फिल्में प्रदर्शित हुईं।

सवाल इमेज का : उन दिनों कला तथा व्यावसायिक फिल्मों की धारा में सुरुचिपूर्ण कलात्मक फिल्मों की एक नयी धारा की शुरुआत हो चुकी थी और इस तरह की फिल्में लोकप्रिय एवं व्यावसायिक रूप से सफल भी हो रही थीं। इस तरह की फिल्में बनानेवाले सफल फिल्मकार थे—ऋषिकेश मुखर्जी, असित सेन, श्याम बेनेगल, बासु चटर्जी, गुलजार आदि। निर्देशक गुलजार की 'मेरे अपने', 'कोशिश' ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की थी। अतएव जीतेंद्र के बेकारी के दिनों में गुलजार ने जीतेंद्र को लेकर फिल्म 'परिचय' का निर्माण किया, जो हालीवुड की सफलतम फिल्म 'साउंड आफ म्यूजिक' पर आधारित थी। 'परिचय' से १९७३ में सशक्त अभिनेता के रूप में जीतेंद्र की न केवल पहचान बनी, बल्कि उनकी पुनः फिल्मों में वापसी भी हुई। 'परिचय' की सफलता से प्रेरित होकर गुलजार ने जीतेंद्र को लेकर एक और फिल्म 'खुशबू' बनायी। जीतेंद्र ने, इस दौरान लीक से हट कर बनी 'एक ही रास्ता', 'संतान', 'संकोच', 'दुल्हन', 'प्रियतमा', 'तुम्हारी कसम', 'उधार का सिंदूर' आदि फिल्मों में भी काम किया। लेकिन बहुत जल्दी उसका भ्रम टूट गया कि इस तरह की फिल्मों से उसका कैरियर स्थापित होनेवाला नहीं। लेकिन इस भ्रम को सबसे ज्यादा तोड़ा गुलजार ने। जीतेंद्र ने उन्हें अपनी फिल्मों के निर्देशन का भार इस आशा से सौंपा था कि वे अपनी दूसरी फिल्मों में उसे नायक की भूमिका देंगे, लेकिन गुलजार ने उसके बजाय जब संजीव कुमार को ही अपनी फिल्मो में रिपीट करना शुरू कर दिया, तो इमेज बदलने की उसकी अभिलाषा पर तुषारापात हो गया।

एक पारिवारिक फिल्म में : जीतेंद्र और रेखा

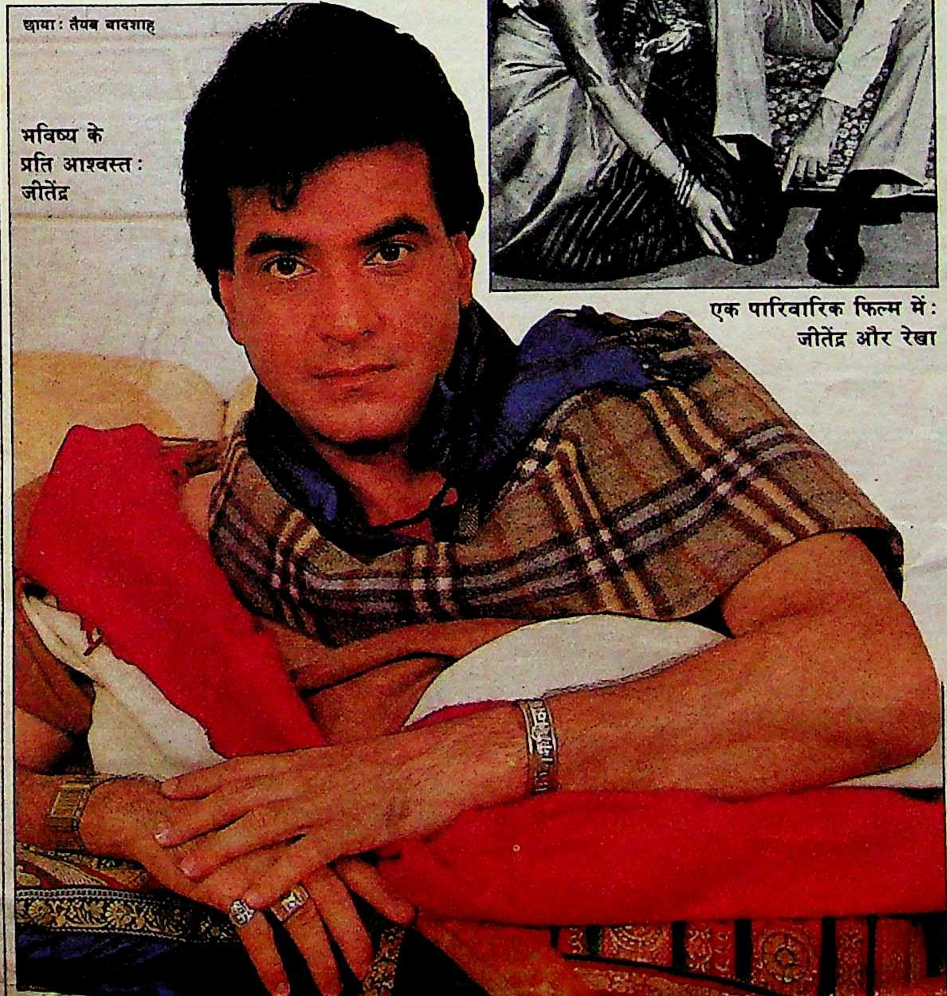
छाया : तैयब बादशाह

भविष्य के प्रति आश्वस्त : जीतेंद्र

मद्रास संपर्क : मद्रास के निर्माताओं के साथ जुड़ते ही जीतेंद्र का सोया भाग्यसितारा अचानक पुनः देदीप्यमान हो उठा। एसवी राजेंद्र सिंह ('मेरी आवाज सुनो') ने जीतेंद्र को एक नयी शख्सीयत दी और तमिल-तेलुगू की सुपरहिट फिल्मों का रीमेक हिंदी में कर बंबइया फिल्म इंडस्ट्री की नींव इस कदर हिला दी कि अभिताम बच्चन से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तथा गोविंदा तक अपनी फिल्मी पकड़ के लिए दक्षिण के इन निर्माता-निर्देशकों का मुंह जोहने के लिए विवश हुए, बल्कि बंबई के तमाम निर्माताओं ने दक्षिण के इन निर्देशकों को लेकर फिल्में बनानी शुरू कर दीं।

लेकिन जीतेंद्र के उसी गढ़ (दक्षिण) में अब मिथुन चक्रवर्ती ने बुरी तरह से छेद कर दिया है और उसके 'अपने' निर्माता-निर्देशकों की फिल्में हथियानी शुरू कर दी हैं। गोविंदा, चंकी पांडे के अलावा अनिल कपूर का भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और इसमें सहायक बनीं जीतेंद्र की ही तीन हीरोइनें—श्रीदेवी, जयाप्रदा एवं भानुप्रिया।

संकट-दर-संकट : पिछले वर्ष जीतेंद्र की एक-एक कर सभी फिल्में बाक्स आफिस पर बुरी तरह से पिट गयीं, तो बाक्स आफिस पंडितों ने जीतेंद्र की चलाचली की भविष्यवाणी कर दी। इधर जीतेंद्र के रुख का बंबइया फिल्मों के प्रति बढ़ने का भी असर उसके दक्षिण-निर्माता-निर्देशकों पर पड़ा। एक क्षण को तो ऐसा लगने लगा जैसे जीतेंद्र एक दशक पूर्व के संकट के दौर में पहुंच गया है। लेकिन १९८८ ने खतम होते-होते उबार लिया। एक महीने के भीतर उसने २२ फिल्मों का मुहूर्त किया और १९९० तक की उसकी सारी तारीखें बुक हो गयीं।

"यह गलत है कि मेरा मार्केट खतम हो गया है", कहते हैं जीतेद्र। वे दिसंबर '८८ की स्थिति से अभी भी उल्लसित हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग मानते हैं कि जीतेंद्र की पुनः वापसी हुई है फिल्मों में। जब वे आ गये हैं, तो अगले पांच वर्षों तक उन्हें कोई नहीं डिगा सकता है—आखिर वे बाक्स आफिस के ऐसे गणितज्ञ हैं जिनका भाग-जोड़-घटाना कभी भी गलत नहीं हुआ है।

—रवींद्र श्रीवास्तव

मिले सुर मेरा तुम्हारा...

१९८७ में दूरदर्शन तथा लोकसंचार परिषद, दिल्ली ने भारत की सभी प्रमुख विज्ञापन एजेंसियों को एक सर्कुलर भेज कर उनसे राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित लघु फिल्म बनाने की योजना तथा रूपरेखा आमंत्रित की, तो जिसने सबसे पहले अपनी रूपरेखा भेजी और उस पर फिल्म बनाने की अनुमति भी प्राप्त कर ली, वह थी बंबई की प्रख्यात विज्ञापन एजेंसी आग्लिबी बेंसन ऐंड मैथर (ओब्रीएम) तथा उसके क्रियेटिव डायरेक्टर सुरेश मलिक। उनकी फिल्म रूपरेखा का शीर्षक था— 'हर दिल में जगायें राष्ट्रज्योति'। इसके लिए उन्होनें मुख्य पात्र के रूप मे विभिन्न खेलों के प्रमुख खिलाडियों को पात्र बनाया था, क्योंकि वे आसानी से मिल सकते थे और उनका आम आदमी के मन में भी काफी क्रेज था। इस तरह मशाल लेकर दौड़ते २४ खिलाड़ियों को विभिन्न स्थानों पर शूटिंग कर उन्होंने १० दिन के भीतर फिल्म तैयार कर दूरदर्शन के पास भेज दिया, जिसे १५ अगस्त, १९८७ को नेशनल नेटवर्क पर प्रदर्शित किया गया।

'राष्ट्रज्योति' लघु-फिल्म की सफलता से प्रभावित दूरदर्शन ने इसी शृंखला की दूसरी फिल्म बनाने के लिए सुरेश मलिक को सीधे आमंत्रित किया। इस बार का आमंत्रण कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि 'राष्ट्रज्योति' में संवाद तथा भावाभिव्यक्ति न होने के कारण उसे बनाना आसान था। फिर उसे प्रभावशाली बनाने में संगीतकार लुई बैंक के तेज संगीत ने विशेष योगदान दिया था। अब उन्हें इससे भी बेहतर और कहीं अधिक प्रभावशाली फिल्म बनाकर पेश करनी थी।

"मैं चाहता था कि यह नयी फिल्म 'राष्ट्रज्योति' का मात्र द्वितीय संस्करण न साबित हो," सुरेश मलिक का कहना है, "इसका प्रस्तुतीकरण कहीं और भारतीय-परक हो, ताकि आम दर्शक के मन में कहीं और अधिक गहराई तक राष्ट्रीय भावना की पैठ बन सके।"

अपने सहयोगी पीयूष पांडे के साथ मिलकर लिखे गीत 'मिले सुर मेरा-तुम्हारा, तो सुर बने हमारा' को पहले अलग-अलग पात्रों के साथ गवाने का उन्होंने निश्चय किया, फिर उसे विभिन्न भारतीय भाषाओं में गवाने का निर्णय किया। संगीत की धुन बनाने की जिम्मेदारी पीपी वैद्यनाथन तथा लुई बैंक पर सौंपी और राग के लिए भैरवी राग का चुनाव किया, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा राग था, जिसे किसी भी भारतीय संगीत में ढाला तथा किसी भी प्रहर गाया जा सकता था। कंपोजीशन की जिम्मेदारी धीरज ढांव ने निभायी। इस गीत को भीमसेन जोशी, डा० बालमुरली कृष्णन, लता मंगेशकर के मुख्य स्वरों में तथा कविता कृष्णामूर्ति, सुषमा श्रेष्ठ, लीला घोष, घनश्याम वासवानी, पंकज मित्रा, रमा मणि, सुरेश मलिक आदि १३ गायकों तथा १७५ कोरस गायकों से गवाया गया। उस समय लता मंगेशकर के लंदन में होने के कारण उनके गीत की रिकार्डिंग पहले एक नयी गायिका की आवाज में की गयी जिसे बाद में लता मंगेशकर ने उसी टाइमिंग में अपनी आवाज में, बंबई आकर, रिकार्ड करवायी। हमेशा सफेद एवं सादी साड़ी पहननेवाली लता मंगेशकर ने बांह के ऊपर, अपने साथ लाया तिरंगा पट्टा पिन कर लगा लिया, ताकि माहौल को राष्ट्रीय एकता के जनजागरण से जोड़ा जा सके और तिरंगेपन के रंग को भर कर उसका अहसास कराया जा सके।

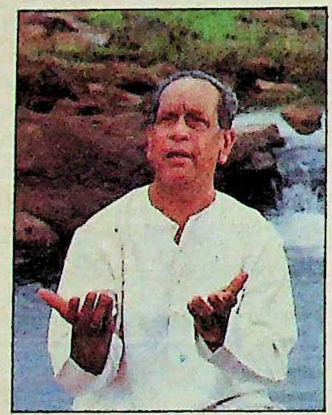

भीमसेन जोशी

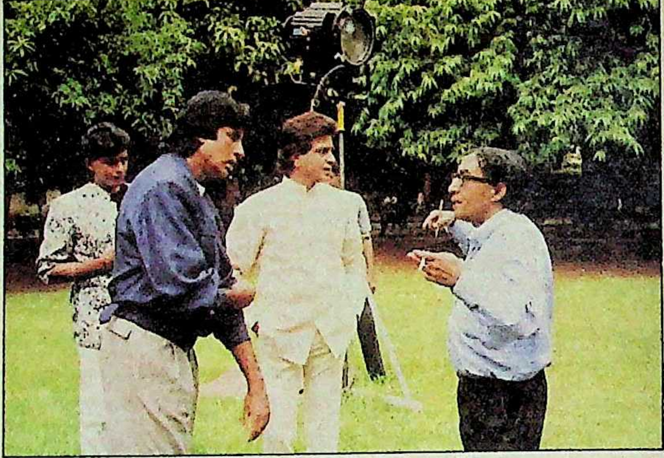

अमिताभ, मिथुन और जितेंद्र को निर्देश देते हुए सुरेश मलिक

सुरेश मलिक इस फिल्म को साढ़े सात मिनट की बनाना चाहते थे और सभी प्रातों के प्रमुख कलाकारों को किसी-न-किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहते थे। सितारों-कलाकारों तथा प्रमुख शख्सीयतों की सूची काफी लंबी थी। उसमें मदर टेरेसा, दिलीप कुमार, राजकपूर भी शामिल थे और समय था सिर्फ डेढ़ महीना जिसमें १० दिन गाने की रिकार्डिंग आदि में ही खर्च हो चुके थे। मदर टेरेसा तथा दिलीप कुमार के विदेश में होने तथा राजकपूर के असामयिक निधन के कारण उन्हें नहीं जोड़ा जा सका।

फिल्म की शूटिंग समूचे भारत में की गयी। मद्रास में सूर्योदय तथा सागर तट पर कमल हासन, केआर विजया, सुधारानी, रेवती प्रताप, एस वेंकट राघवन तथा उनकी पत्नी रजनी, रामनाथ कृष्णन, उनकी पत्नी ललिता तथा बेटी गौरी के दृश्य लिये। कश्मीर में ११ हजार फुट की ऊंचाई से चंदनवाड़ी तथा श्रीनगर में नागिन लेक, एयर फोर्स के हेलिकाप्टर से ताजमहल, जयपुर के निकट रेगिस्तान, बंगलौर में विशालकाय चट्टानों तथा पेरियार में हाथियों के दृश्य जाकर फिल्माये। बंगलौर में ही ईएस प्रसन्ना, कल्पना कुटैय्या तथा बंसी मनैपांडा के अलावा तेलुगू के जाने-माने सितारे ललिता अरूयर एवं सत्यनारायण राजू के साथ शूटिंग की गयी। बंगाली नाविकों का दृश्य दक्षिणेश्वर (कलकत्ता) में फिल्माया गया। वहां की मेट्रो ट्रेन से निकलने का सीन सुचित्रा मित्रा, अमला शंकर, पीके बनर्जी (सिर पर हाथ फेरते हुए), चुन्नी गोस्वामी, सुनील गांगुली, नीरेंद्र चक्रवर्ती, आनंद शंकर पर चित्रित किया। शिलांग के निकट बरा पानी के पास फिल्मांकित नृत्य करते हुए सात युगल उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 'सेवन सिस्टर्स' के नाम से प्रख्यात मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम तथा नगालैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गोवा की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध गोवानी कार्टूनिस्ट मारिया मिरांडा को बंबई से पंजिम बुलाया गया। गुजरात के प्रतिनिधित्व के लिए नृत्यांगना मल्लिका सारा भाई को चुना गया, लेकिन शूटिंग गुजरात के बजाय बंबई के निकट ही की गयी। ऊटी में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती तथा बंगलौर में वहीदा रहमान वाले दृश्य फिल्माये गये। अंतिम दृश्य (सफेद, हरे तथा नारंगी रंग के परिधान पहने बच्चों के—तिरंगे के प्रतीक) शिमला के लारेंस स्कूल के दो सौ बच्चों पर लिये गये। सबसे ज्यादा दृश्यों की शूटिंग बंबई में हुई। फिल्म सिटी में निर्मित 'तमस' के एक सेट पर, उसके कलाकारों के साथ, गीत का एक पूरा बोल पंजाबी लहजे में फिल्मांकित किया गया। शबाना आजमी, हेमा मालिनी, तनूजा, नरेंद्र हिरवानी के साथ बंबई के विभिन्न लोकेशनों एवं स्टूडियो में शूटिंग की गयी, जबकि

यह वोल्टेज के उतार चढ़ाव से भली भांति निपट लेता है

केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर के लिए वोल्टेज के उतार चढ़ाव एक साधारण सी बात है। तथा "सब से ठंडा" हर स्थिति से भली भांति निपटता है।

इसका राज़ है इसका 'पावर सेवर' कॉम्प्रेसर। वोल्टेज के तीव्र उतार चढ़ाव सहन करने के लिए सुदृढ़ निर्मित। यह शीघ्र ठंडा करता है तथा उस से भी शीघ्र बर्फ़ बनाता है। चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो। यह बिजली की न्यूनतम खपत करता है।

केल्विनेटर का एक और आश्चर्यजनक गुण है — विशाल स्टोरेज क्षमता। इसके कोने-किनारे-रहित विशिष्ट अन्दरूनी डिज़ाइन में अधिकतम स्थान का उपयोग हो सकता है।

सुदृढ़, सम्पूर्ण स्टील निर्माण तथा मज़बूत ए बी एस लाइनर इसके बाहरी एवं अन्दरूनी भाग को अधिक मज़बूती, तथा अधिक टिकाऊपन प्रदान करते हैं।

आपके चयन के लिए यह विभिन्न मॉडलों तथा आकर्षक रंगों में उपलब्ध है।

इसी कारण जब भी आप ऐसा रेफ्रिज़रेटर चाहें जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कुशलतापूर्वक कार्य करे, तो केल्विनेटर खरीदिए।

विक्रय एवं सर्विस के लिए :

एक्सपो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टावर, 26 राजिन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली-110 008.

Mutual-4711CHN

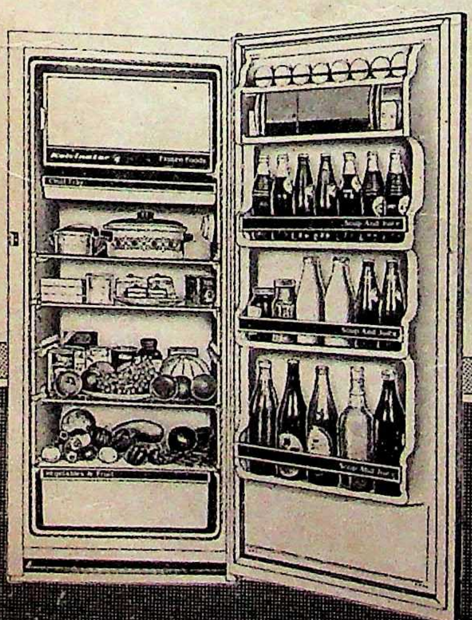

REFRIGERATORS
DEEP FREEZERS

केल्विनेटर

रेफ़्रिजरेटर

"इसकी ठण्डक...बेमिसाल!"

Regd. No. AD-6
Lic. No. U/AD-2

MAYA
February 1st 1989

RNI No. RN 2391/57
Rs. 6.00 Per Copy

152
30/11/89
874
1/12/89
618
8/12/89
824
7/12/89
11/12/89 B
698

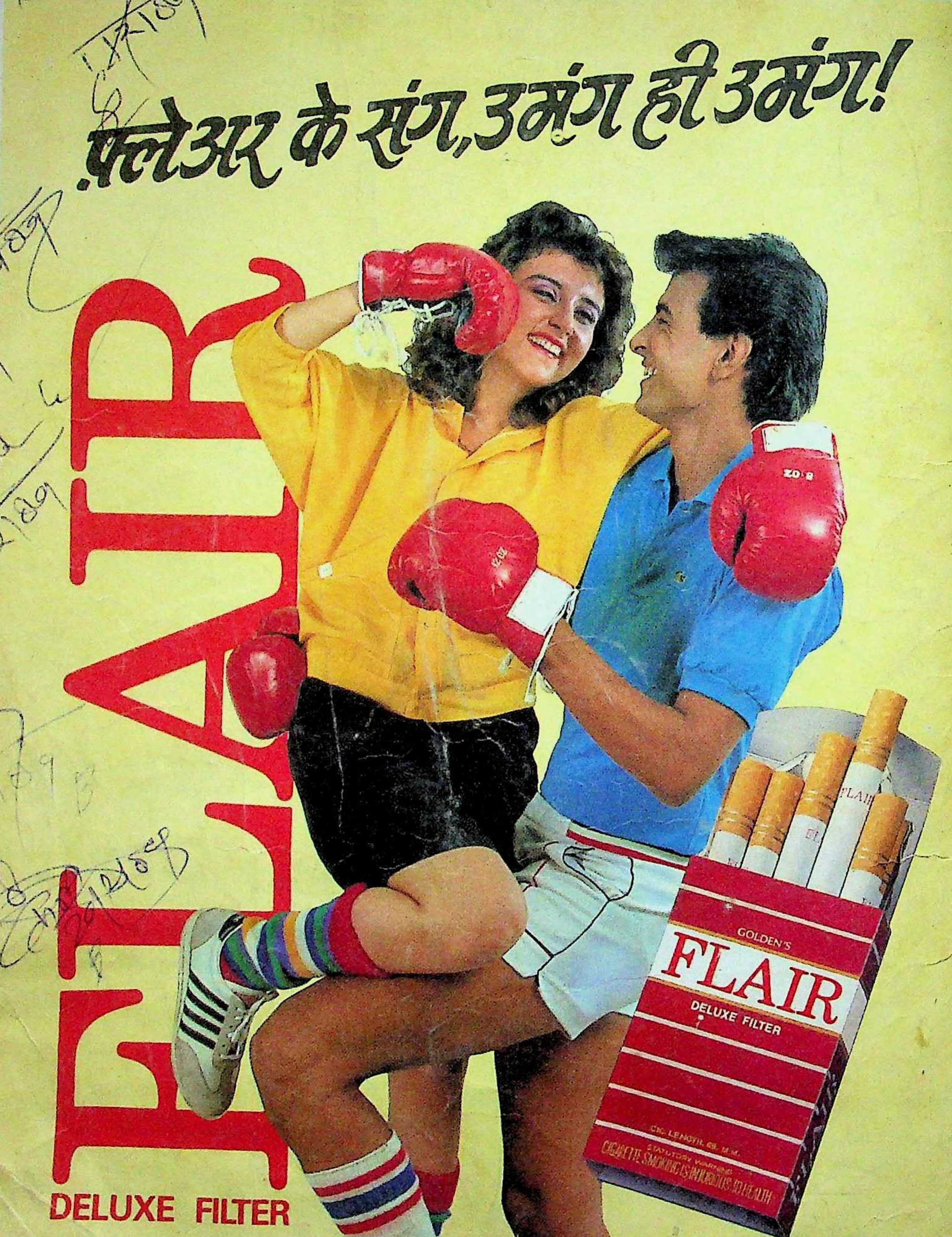
फ्लेअर के संग, उमंग ही उमंग!
FLAIR
DELUXE FILTER
GOLDEN'S
FLAIR
DELUXE FILTER
CIG. LENGTH 69 M.M.
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
Govan/FDF-2/B/88/HN
वैधानिक चेतावनी: सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

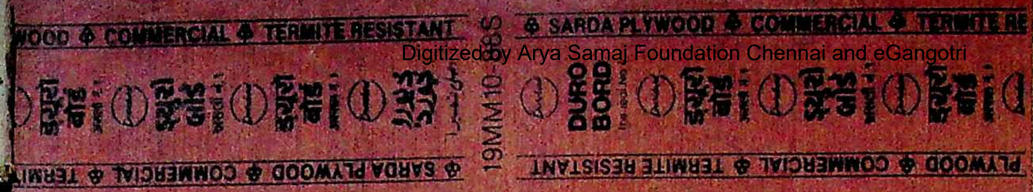
SARDA PLYWOOD ♣ COMMERCIAL ♣ TERMITE RESISTANT
DURO BORD
19MM10-885

पुस्तकालय
गु० कां० विश्वविद्यालय
हरिद्वार

20/7/84

बोर्डरुम में दुर्घटना

सोमवार, ३ अक्टूबर, सुबह ११ बजे। बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।

मगर हो गया कुछ और!

प्रबन्ध निदेशक ने देखा एक खून। अपनी कॉन्फ्रेंस टेबल का खून। छानबीन से खूनी पकड़ा गया—एक साधारण ब्लॉकबोर्ड। इसके इस्तेमाल ने सारे किये-कराये पर पानी फेर दिया। निश्चय ही इसके लिए चाहिए था एक भरोसेमंद ब्लॉकबोर्ड। सर्वसम्मति से फैसला किया गया। प्रत्येक प्रतिष्ठित कम्पनी के लिए चाहिए—ड्यूरोबोर्ड। एक असाधारण व विश्वसनीय ब्लॉकबोर्ड। ड्यूरोबोर्ड—जिसका आकार रहे एकसार, साल दर साल। असली नं. १। न झंझट, न परेशानी। क्योंकि ड्यूरो ही है हीरो। ड्यूरो—क्योंकि इसके मुकाबले में कोई नहीं।

ड्यूरो–
ब्लॉकबोर्ड का हीरो

Durobord
BLOCKBOARD
TERMITE RESISTANT
a Sarda Plywood Product

Durobord™

असली नं - १

नकल से
दुहरी सुरक्षा

लेबल और स्ट्रिप असली ड्यूरोबोर्ड की सही पहचान।

सारदा प्लाइवुड
इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
वर्क्स: जेपुर (आसाम)
जनरल सेल्स ऑफिस:
१/७, देशबंधु गुप्ता रोड, नई दिल्ली ११० ०५५

DPS/SPL-883 HIN

बचाव कार्य में सफलता ने दिया वो चैन और संतोष भरा अहसास
जो मुझे मिलता है
अपनी मनपसंद रेड एण्ड व्हाईट किंग्ज़ के साथ।
You can't beat the feeling
RED & WHITE
KINGS
MADE IN INDIA
RED & WHITE
KINGS
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
अब नए पैक में।
वैधानिक चेतावनी.
सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
everest/d88/HMA/395 hin

माया

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ६०, अंक ४ २८ फरवरी, १९८९

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७३०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६५९६८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय: स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९१०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©

इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

आवरण कथा

३०

तमिलनाडु की हार के बाद इंकाशासित राज्यों में खुला विद्रोह शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के इस्तीफे के बाद नेता-चयन में जिस तरह की तनातनी हुई, बिहार में आजाद को उलटने के लिए विक्षुब्ध विधायकों ने जो ठानी और गुजरात-राजस्थान में असंतुष्टों ने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, उसका राजीव गांधी को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा? क्या राजीव गांधी इस विद्रोह को दबा पायेंगे?

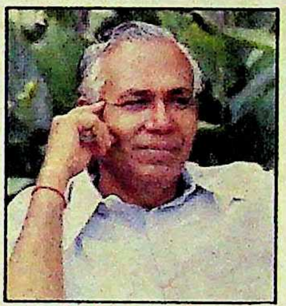

३५ कैसे टिके आजाद?

बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के विरुद्ध विक्षुब्धों की मुहिम क्या रंग दिखायेगी?

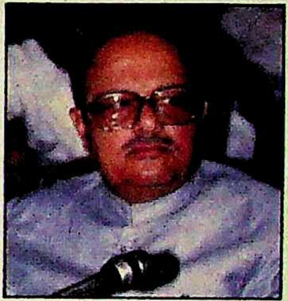

४० अर्जुन सिंह

अर्जुन सिंह के इस्तीफे के बाद वोरा को उत्तराधिकारी बनाने में आलाकमान के सामने क्या नजारा पेश हुआ?

५६ मुलायम सिंह यादव

जनता दल के महारथियों ने मुलायम सिंह यादव को ५१ लाख रुपए मनमाने ढंग से खर्च करने की छूट क्यों दी?

१७ महाकुंभ

मौनी अमावस्या के मुख्य कुंभ पर्व पर अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन कुंभ का कुल मिलाकर स्वरूप क्या रहा?

६९ सुब्रह्मण्यम स्वामी का खेल

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी विपक्षी नेताओं पर हमले क्यों कर रहे हैं?

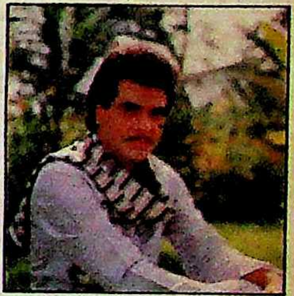

८२ जीतेंद्र

बहुचर्चित हीरो जीतेंद्र ने अपने तीन दशकों के फिल्मी सफर में क्या पाया, क्या खोया?

दिल्ली दरबार: बहुत उदास है रात १०
फोटोफीचर १३
प्रसंगवश: नशीले पदार्थ: क्या मृत्युदंड इसका इलाज है? ४५
राजस्थान: धौलपुर के बंदी कैंप में पुलिस का कहर ४९
राजस्थान: मंत्री के पतिदेव क्यों परेशान हैं? ५२
राजस्थान: उमा शर्मा: हत्या या आत्महत्या? ५४
उत्तर प्रदेश: जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस में भितरघात ५८
जम्मू-कश्मीर: हिंदू-सिख दंगे के लिए कौन जिम्मेवार? ६०
महाराष्ट्र: बगावत की गरमाहट ६४
विदेश: हिरोहितो के बाद जापानी साहस को चुनौती ७२
देश: वामपंथी दलों ने क्या खोया, क्या पाया? ७४
दूरदर्शन: मिले सुर मेरा तुम्हारा... ८४
माध्यम: अखबारी युद्ध ८५
धनधंधा ८६
अर्थतंत्र: क्या महंगाई पर नियंत्रण संभव है? ८८
उपकरण ९०
स्त्री: विसंगतियों का कुंभ ९२

आवरण पारदर्शी
सुनील सक्सेना
(राजीव गांधी)
मुकेश सहगल
(कुंभ)

From the House of Cuticura
Curoline
Antiseptic Skin Cream
With Neem Oil

नीम से बनी, यह बड़े गुणवाली करे आपकी त्वचा की पूरी रखवाली.

Orbit/MP-C/731-89 Hin

नयी क्यूरोलीन में है बरसों से आजमायी हुई नीम की सारी खूबियां. इसमें मिले आयुर्वेदिक पदार्थ,त्वचा पर हल्के-हल्के असर करते हैं. क्यूरोलीन त्वचा के कटने-छिलने और खरोंच आदि में ठंडक पहुंचाती है. फटे होठों, चकत्तों और जलने के छोटे-मोटे घावों में राहत दिलाती है.

क्यूरोलीन

त्वचा-रक्षक एन्टीसेप्टिक क्रीम

त्वचा की रखवाली करने वाले नीम - गुण
— अब क्रीम में.

एक आयुर्वेदिक औषधि

राजीव झुकेंगे या झुकायेंगे ?

'माया का ताजा अंक (१५ फरवरी, १९८९) मिला। आवरण कथा 'चीन-पाक समझौते के लिए राजीव झुकेंगे या झुकायेंगे ?' पढ़ी। बहुत दिनों बाद 'माया' ने राष्ट्रीय राजनीति से ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी आवरण कथा आयोजित की। इसमें दो राय नहीं कि राजीव गांधी ने चीन और पाकिस्तान की यात्राएं कर अच्छे संबंधों की शुरुआत की पहल की, लेकिन जितना महत्व यात्राओं का नहीं, उससे अधिक उनका प्रचार किया गया। इन मामलों का असली महत्व तो तब उजागर होगा, जब कुछ ठोस परिणाम सामने आयें, कुछ समस्याएं हल हों। पूरी कथा पढ़ने के बाद, जो बात सबसे अधिक खटकती है, वह यह कि इसमें पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा बहुत कम है, जबकि चीन को लेकर पेज-के-पेज भरे हुए हैं। फलस्वरूप कथा कुछ एकांगी-सी हो गयी है। बहरहाल प्रयास सराहनीय है। **—संजय कोठारी, १८ पाली रोड़, बंबई**

बड़े बजट की फिल्मों के लिए खतरे की घंटी

१५ फरवरी, १९८९ की 'माया' में प्रकाशित लेख 'केबिल टीवी : बड़े बजट के फिल्मों के लिए खतरे की घंटी' काफी तर्कपूर्ण एवं सामयिक लगा। आज फिल्म उद्योग टीवी साम्राज्य एवं वीडियो पाइरेसी' के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है। पिछला वर्ष हिंदी फिल्मों के लिए सबसे अशुभ रहा, क्योंकि १४० फिल्मों में मात्र बारह ही सफल हुई थीं। एकमात्र कम बजट की फिल्म 'कयामत से कयामत तक' ही सुपरहिट रही। अब निर्माता बड़े बजट की मल्टीस्टार फिल्में बनाने में हिचकने लगे हैं। अमिताभ की फिल्म 'गंगा-जमुना-सरस्वती' को दर्शकों द्वारा नकार दिये जाने से स्थिति अत्यंत विस्फोटक होती जा रही है। क्योंकि केवल अमिताभ पर इंडस्ट्री का २५ फिल्मों में ४ करोड़ के हिसाब से १०० करोड़ रुपया लगा हुआ है। **—दीपक कुमार दीक्षित, छज्जूबाग, पटना, बिहार**

कांग्रेस बनाम कांग्रेस, विपक्ष बनाम विपक्ष

आवरण कथा 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस, विपक्ष बनाम विपक्ष' पढ़ी। यह तो जगजाहिर है कि विपक्षी नेता निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर आपस में मार-धाड़ मचाये हुए हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता किस स्वार्थ से प्रेरित होकर आपस में लहूलुहान हो रहे हैं, समझ में नहीं आता। कम-से-कम राजनीतिज्ञों को तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। **—ललित कुमार मिश्र, विष्णुगढ़ (हजारीबाग), बिहार**

'माया' का ३१ जनवरी '८९ का अंक आद्योपांत पढ़ गयी। आवरण कथा 'कांग्रेस बनाम कांग्रेस, विपक्ष बनाम विपक्ष' में जननेताओं के चरित्र एवं दलों के आंतरिक कलह और बिखराव का निष्पक्ष ब्योरा दिया गया है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही अविश्वास एवं गुटबंदी के शिकार हैं। राष्ट्रीय, राज्यीय या स्थानीय स्तर के सभी नेता रोगग्रसित हैं। उनके चिंतन एवं आचरण का प्रत्यक्ष प्रभाव जन साधारण पर पड़ता है। फलतः नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। प्रजातंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। **—कुमारी अंजना तिवारी 'पप्पी', पोड़ी, उपरोड़ा, बिलासपुर, मप्र**

राजीव गांधी की चीन यात्रा

'माया' में प्रकाशित लेख 'राजीव गांधी की चीन यात्रा' पढ़ा, जो तथ्यों से पूर्ण है। इस संबंध में एक तथ्य यह भी है कि सीमा विवाद जैसे नाजुक और गंभीर मसले पर शीघ्र ही कोई समझौता हो जाये, इसकी तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरह से भारत-चीन संबंधों में सद्भावपूर्ण और सकारात्मक मोड़ आया है, उससे इस समस्या के हल हो जाने की आशा है। **—पीसी श्रीवास्तव, सैदपुर, गाजीपुर**

प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बारे में 'दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की शुरुआत' शीर्षक कथा (माया ३१ जनवरी '८९) पढ़ी। ३४ वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा थी। इस यात्रा से दोनों देशों के मध्य चले आ रहे तनाव में निश्चित रूप से कमी आयेगी।

भारत चीन संबंधों में सीमा-विवाद एक नाजुक मसला है जिसके कारण दोनों देश काफी लंबे समय से कटे से रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों में एक नया उत्साह देखने को मिला है। भारतीय प्रेस ने भी यह माना है कि अबकी बार चीनी नेता वास्तव में गंभीर दिखाई दिये मानो वे इस लंबे चलने वाले तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन इस मसले में हमें ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए और चीन-यात्रा को एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानना चाहिए। हां, यह एक अच्छी शुरुआत जरूर है। **—दिलबाग सिंह, ग्राम—बादली, रोहतक, हरियाणा**

मैं और मेरी तनहाई

बेनजीर की आत्मकथा एक संघर्षशील लड़की की कहानी है, जो हमारी बहनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 'माया' का मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं ? 'माया' ने लगातार आत्मकथा की तीन कड़ियां छापकर हम पाठकों पर भारी अहसान किया है। **—श्रीनिवास सिंह, जगदम महाविद्यालय, छपरा, बिहार**

और क्या करता कमलेश पंत ?

'माया' के ३१ जनवरी वाले अंक में प्रकाशित लेख 'और क्या करता ?' पढ़कर मन को एक जबरदस्त धक्का लगा।

अधुना हमारी सरकार और उसकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आनेवाले ऊपर से नीचे तक के सारे उच्चाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारीगण जिस तरह भ्रष्टाचार, व्यभिचार एवं भाई-भतीजावाद में फंसे हुए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। इसी की एक कड़ी है कमलेश पंत की आत्महत्या। कमलेश पंत के लिए आत्महत्या एक लाचारी थी। चूंकि लैब निदेशक डा० कुमार ने उसे मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित कर दिया था कि उसके लिए यह एक त्रासदी बन चुकी थी। अतएव उसने मौत को ही गले लगाना बेहतर समझा जैसा कि उसके पत्रों से ज्ञात होता है। **—प्रो० अभय आशियाना, संत संध्यादास महिला महाविद्यालय बाढ़, पटना**

अफीम की जकड़बंदी के खिलाफ जेहाद

३१ जनवरी के अंक में 'अफीम की जकड़बंदी के खिलाफ जेहाद' के अंतर्गत नारायण सिंह के सद्प्रयासों की जानकारी मिली। नशे के गर्त में फंसे लोगों को अपनी संस्था के माध्यम से उबारकर वे मानवता की भलाई कर रहे हैं। अफीम के नशे के विषय में यह मान्यता है कि इसे सेवन करनेवाला व्यक्ति जीवनपर्यंत इसका गुलाम बना रहा है, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों को इससे निजात दिलाकर इस धारणा को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। आज इस प्रकार के कार्यक्रमों को व्यापक पैमाने पर चलाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि मादक द्रव्यों की अंधी राहों पर चलनेवाले लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। **—राजन चोपड़ा, जंगपुरा, नयी दिल्ली**

गोवा रंगरली कांड की असलियत

'माया' के ३१ जनवरी '८९ के अंक में छपे लेख 'गोवा रंगरली कांड : कितना सच, कितना झूठ ?' के संदर्भ में यह एकदम स्पष्ट है कि प्रो० शांतिलाल जैन ने इस गोवा भ्रमण को अपनी मनमर्जी के मुताबिक आयोजित किया व छात्रों के विरोध की चिंता न करते हुए भी नाथद्वारा के स्थान पर उदयपुर रात्रि विश्राम किया जिससे उनके भाई को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला। प्रो० जैन ने हर गलत कार्य को करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से संबंधित छात्रों—गोविंद डागा व अयूब कुरैशी को अपने विश्वास में लिया जो

कि उस टूर पर गये एक गुट का नेतृत्व कर रहे थे।

प्रो० जैन द्वारा एक छात्र कैलाश पचोली से ७ रुपए उधार लेना व गोवा की घटनाओं के बारे में अनभिज्ञता दर्शाना उनका अपराधी होना दर्शाता है। स्वयं डागा व कुरैशी इसमें लिप्त रहे। अतः वे प्रो० जैन का समर्थन करने के लिए मजबूर है। एनएसयूआई के लोग बेवजह विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे है।—**अनिल मंडारी, मोती चौक रोड, जोधपुर, राजस्थान**

चाणक्य से बराबरी ठीक नहीं

'माया' का ३१ जनवरी का अंक पढ़ा।

लोकदल-ब की रैली के संचालक भारतीय राजनीति में बुरी तरह पिटे मोहरे बहुगुणा को आपने भारतीय 'राजनीति का चाणक्य' कहा। यह जानकर आपके मापदंड पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने अब तक के सफल एवं देशभक्त राजनीतिज्ञ चाणक्य से बहुगुणा को जोड़ा।—**महेंद्र कुमार कोचर, कटांगी, बालाघाट, मप्र**

हिंदी-चीनी बहनें-बहनें

'माया' (३१ जनवरी '८९) में प्रकाशित ममता कालिया का लेख 'हिंदी-चीनी बहनें-बहनें' में उक्त लेखिका के विचार एकपक्षीय लगे। स्वयं स्त्री होने के नाते लेखिका ने स्त्री जाति की कमियों को नजरअदाज करते हुए स्त्री की दयनीय स्थिति के लिए केवल पुरुष को दोषी ठहराया है जो उचित नही है। आज स्त्री की दयनीय स्थिति के लिए स्वयं स्त्री जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर जब एक मां अपने बेटे की शादी करती है, तब उसकी निगाहें बहू पर कम दहेज पर अधिक रहती है। दहेज के कारण बहू जलाने के अनेक मामलों में सास और ननद का हाथ होता है। ऐसी स्थिति में जब स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बन चुकी है, तब बेचारे पुरुष को दोषी ठहराना क्या उचित होगा?—**मुकेश अग्रवाल, सावन कटरा, आगरा, उप्र**

कौन सी पार्टी दावेदार होगी?

'माया' (३१ जनवरी '८९) में 'राजनीतिक दलों के दलदल की कहानी' पढ़ने से ऐसा लगा कि विपक्ष में अपना अस्तित्व कायम रखने के कारण फासला बढ़ता जा रहा है, तो कांग्रेस में एक दूसरे से बदला लेने की भावना के कारण विरोध है। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस तथा विपक्ष दोनों की स्थिति मजबूत नही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

अतः कहा नहीं जा सकता कि आगामी लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता की दावेदार होगी?
—राजेश्वर राय, ग्राम—ढाजुरा, पोस्ट—बौरवां, गाजीपुर

पापरी बोस अपहरण कांड

'माया' (३१ जनवरी '८९) में प्रकाशित कथा 'पापरी बोस अपहरण कांड' पढ़ी। इस कांड में भागलपुर पुलिस की जिस प्रकार भूमिका रही, उससे पुनः एक बार स्पष्ट हो गया कि सत्ता से जुड़े राजनीतिज्ञ किसी भी स्तर की छूट पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह अकेला कांड बिहार का है, किंतु इस प्रकार के महिलाओं की इज्जत के जुडे कांड पर लीपापोती होने से समाज में असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। हमारी राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार भटक गयी हैं, ऐसी घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है।—**शैलेंद्र सिंह तरकर, सनहौली, खगड़िया, बिहार**

खंडन

१५ जनवरी, १९८९ की 'माया' में 'बिहार परिशिष्ट' के अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण वाले लेख में मेरी प्रतिक्रिया को जिस रूप में छापा गया है, वह मेरे द्वारा आपके प्रशांतजी को दिये गये साक्षात्कार में कही गयी मेरी बातों से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैंने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार एमेच्योर एथलेटिक संघ को दिये गये एवं दिये जा रहे अनुदान के संबंध में बातें कही थी एवं संघों को दिये जाने वाले अनुदान के नियम तथा प्रक्रिया के ऊपर अपनी टिप्पणी की थी, न कि अनुदान समिति के किसी सदस्य पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी जैसा कि उपर्युक्त लेख में आपने छापा है।
—रामचंद्र, कोषाध्यक्ष, बिहार एमेच्योर एथलेटिक एसोसियेशन, पटना

हमने इसको (भ्रष्टाचार को) खतम करने की कोशिश की है, पर हमारे हाथ बंधे हैं। हम जितने ही कानून लागू करते हैं, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।—**राजीव गांधी, दिल्ली में**

मैं एक डूबते हुए जहाज में बैठे रहने की बेवकूफी क्यों करूं?—**राजमंगल पांडेय, लखनऊ में**

संगम में नग्न स्नान कर नागा संन्यासी त्रिवेणी का अपमान कर रहे हैं।—**स्वामी स्वरूपानंद (शंकराचार्य, शारदापीठ), कुंभ मेले में**

विरोधी पक्ष के नेता ऐसे फूल हैं जो बारिश के दौरान तो खूब दिखायी देते हैं, मगर बारिश खतम होते ही जाने कहां लापता हो जाते हैं।—**गृहमंत्री बूटा सिंह, दिल्ली में**

तमिलनाडु में चुनाव आये तब राजीव गांधी भी आ धमके, लेकिन क्या उस वक्त भी वे आये थे, जब सूखा पड़ा और ट्रेन दुर्घटना हुई थी?—**वीपी सिंह, मद्रास में**

वीपी सिंह

संपूर्ण (महाकुंभ) मेला भी पुलिस का है और उसका आनंद भी पुलिस तथा प्रशासन के लोग ही उठा रहे हैं।—**स्वामी निरंजनदेव तीर्थ (शंकराचार्य, गोबर्धनपुरी), प्रयाग में**

मैं इनकी (मोरारजी देसाई की) जगह उन मजदूरों और कामगारों को कद्र देती जो मुल्क की खुशहाली के लिए अपना पसीना बहाते हैं।
—बेनजीर भुट्टो, इस्लामाबाद में

तमिलनाडु का चुनाव पानीपत की चौथी लड़ाई थी, जिससे देश को नयी दिशा मिलेगी। इस (तमिलनाडु) चुनाव के साथ ही दक्षिण में कांग्रेस-इ का सफाया हो गया है और अगली लड़ाई अब उत्तर भारत में लड़ी जायेगी।—**देवीलाल, चंडीगढ़ में**

इन चुनाव-नतीजों से लोकसभा के अगले चुनाव-नतीजों का रुख तय हो गया है—यह राजीव गांधी की निजी हार है।—**ईएमएस नंबूदिरीपाद, नयी दिल्ली में**

कांग्रेस-इ से हाथ मिलाने में खबरदारी बरतें—यह हाथ आपकी जेब काट लेगा और उसकी रकम किसी स्विस बैंक में जमा कर देगा।
—वीपी सिंह, मदुरै में

मैंने शांति कायम कर दी, किंतु अब मैं 'टायलेट पेपर' की तरह फेंका जा रहा हूं।—**लालडेंगा, ऐजल में**

मैंने कभी यह नहीं कहा कि भाजपा (हमारा) प्रमुख शत्रु है।—**ईएमएस नंबूदिरीपाद**

कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं विवाद बढ़ाने के लिए ही जन्मा हूं।
—अमिताभ बच्चन, दिल्ली में

अमिताभ बच्चन

मैं सेक्स (वासना) का प्रतीक नहीं हूं, मैं कभी अपने को सेक्सी (कामुक) नहीं समझता, न ही महसूस करता हूं।—**इमरान खां, स्टारडस्ट में**

राष्ट्रपति चाहें तो शौक से जेल में डाल सकते हैं मुझे, लेकिन मैं सती होनेवाली महिलाओं में अपना विश्वास बनाये रखूंगी।—**राजमाता विजया राजे सिंधिया, बंबई में**

उन्होंने (विजया राजे सिंधिया ने) 'आस्था के संवैधानिक अधिकारों' की आड़ में सती का समर्थन कर महिलाओं के 'जीने के हक' पर चोट की है।—**मृणाल गोरे, बंबई में**

हां, (शिव) सेना ने बंबई महानगरपालिका में पैसा बनाया है, पर यह भ्रष्टाचार हमें कांग्रेस ने ही सिखाया है।—**बाल ठाकरे, बंबई में**

डायमंड पाकेट बुक्स में

राजहंस
दरार
राजहंस

राजहंस
का नया उपन्यास
दरार

जनप्रिय लेखक
ओमप्रकाश शर्मा
का जासूसी उपन्यास
वासना के पुजारी

जनप्रिय लेखक
ओमप्रकाश शर्मा
वासना के पुजारी

कुमार कश्यप
का नया जासूसी उपन्यास
काली बस्ती

राहुल
का नया रोमांचकारी उपन्यास
लाशों का अपमान

समीर
का नया उपन्यास
दौलत और ममता

जेम्स हेडली चेईज़
का नया जासूसी उपन्यास
सुन्दरी का चैलेंज

चेतना
का नया उपन्यास
सपने सुहाने

विक्की आनन्द
कांपती आवाज़

लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार
विक्की आनन्द
का नया उपन्यास
कांपती आवाज़

डायमंड पाकेट बुक्स प्रा. लि.
2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

केएन सिंह की मुसीबत

जब भोपाल में अर्जुन सिंह की जगह दूसरे मुख्यमंत्री को चुनने के लिए मारकाट चल रही थी, तो दिल्ली के २४ अकबर रोड स्थित इंका मुख्यालय पर बैठे महामंत्री केदार नाथ सिंह ने एक बयान दे मारा, "मप्र में पार्टी हाईकमान ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं बनाया है। वहां का विधायक दल जो नेता चुनेगा, वही पार्टी हाईकमान को स्वीकार होगा।"

जैसे ही केदार बाबू का यह बयान संवाद समितियों के टेलीप्रिंटरों के जरिये भोपाल पहुंचा, वैसे ही एक ओर दिल्ली से गये प्रेक्षकों—गुलाम नबी आजाद, वीर बहादुर सिंह तथा दरबारा सिंह को सांप सूंघ गया तथा दूसरी ओर अर्जुन सिंह समर्थक दिग्विजय सिंह को और समर्थन जुटाने के लिए सशक्त आड़ मिल गयी। अर्जुन सिंह के लोगों ने केदार नाथ सिंह के उस बयान के आधार पर यह कहना शुरू कर दिया कि गुलाम नबी आजाद मप्र के विधायकों को मूर्ख बना रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने मप्र इंका विधायक दल को अपना नया नेता चुनने की पूरी छूट दे रखी है। बस इस पर मामला काफी तूल पकड़ गया। दूसरी ओर दिल्ली से गये प्रेक्षक खुले तौर पर विधायकों से यह नहीं कह पा रहे थे कि उनको दिग्विजय सिंह को नहीं चुनना है।

गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास फोन करके पूछा कि यह केदार नाथ सिंह को इस तरह का बयान देने की इजाजत किसने दी? उनके बयान ने भोपाल में तूफान खड़ा कर दिया है। विधायक हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं और अर्जुन सिंह ने उस बयान का पूरा लाभ दिग्विजय सिंह के लिए उठा लिया है। प्रधानमंत्री निवास से गुलाम नबी आजाद को बताया गया कि केएन सिंह ने यह बयान अपनी ओर से जारी कर दिया होगा। उनको इस तरह का बयान जारी करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसके बाद ही केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह तथा इस्पात मंत्री माखन लाल फोतेदार को भोपाल भेजने का फैसला लिया गया।

दूसरे दिन केएन सिंह को इस तरह का बयान जारी करने के लिए प्रधानमंत्री—निवास से काफी फटकार लगायी गयी। जब भोपाल में बूटा सिंह और फोतेदार से काम नहीं चला, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बम्बई से भोपाल अर्जुन सिंह से सीधे टेलीफोन पर बात की और कहा कि "मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बना दें।" उसी के बाद अर्जुन सिंह माने और उन्होंने अपने समधी दिग्विजय सिंह को मैदान से हटा लिया।

अब तो मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बन गये। लेकिन केएन सिंह अभी तक अपने उस बयान से सहमे हुए हैं और बिहार के मामले में जब पत्रकारों ने उनसे कुछ बयान देने को कहा, तो वे मुस्करा कर टाल गये, "अभी भोपाल के बयान से उभर नहीं पाये हैं, एक नयी मुसीबत में नहीं फसेंगे।"

प्रधानमंत्री अमेठी में 'असुरक्षित'

क्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी का विमान उनकी पिछली अमेठी यात्रा के दौरान फुर्सतगंज के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी की हवाई पट्टी पर बिना पर्याप्त तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में उतर गया? बताया जा रहा है कि अकादमी के निदेशक कैप्टन ढेवर मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं।

पता चला है कि पहले अकादमी की फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर विमानों के उतरने का तकनीकी पक्ष नेशनल एयरपोर्ट अथार्टी के अधीन था। लेकिन कैप्टन ढेवर के अनुरोध पर अथार्टी ने यह काम ८ अक्तूबर, १९८८ को अकादमी को सौंप दिया था। कैप्टन ढेवर को अपनी हवाई पट्टी पर विमान उतरने के तकनीकी पक्ष की पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। लेकिन वे किन्हीं कारणों से नहीं कर पाये। प्रधानमंत्री को २२ नवंबर को पहुंचना था। इसीलिए उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट के प्रभारी अग्निहोत्री को टेलीफोन करके यह कहा कि प्रधानमंत्री के विमान उतरने की तकनीकी व्यवस्था को वे लोग आकर देखें। बताया जाता है कि अग्निहोत्री ने ढेबर से कहा कि चूंकि अब यह हवाई पट्टी उड़न अकादमी को सौंप दी गयी है, इसलिए विमान उतरने की तकनीकी-व्यवस्था करना उनके अधीन नहीं है। इस पर कैप्टन ढेबर ने २१ नवंबर को नेशनल एयरपोर्ट अथार्टी के चेयरमैन सीकेएस राजे से सम्पर्क स्थापित किया। राजे ने कहा कि वे लखनऊ एयरपोर्ट पर अपना विमान भेजकर वहां से आदमी मंगवा लें। मैं निर्देश दिये दे रहा हूं। कैप्टन ढेबर ने उसके बाद अपनी अकादमी से कोई विमान लखनऊ नहीं भेजा, जबकि वहां दो तकनीकी लोग इंतजार करते रहे। उसके बाद अग्निहोत्री ने उन दोनों आदमियों को बस से फुर्सतगंज भेजा। जब तक वे लोग २२ नवंबर को पहुंचें, प्रधानमंत्री का विमान उतर चुका था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को इसकी तुरन्त जानकारी हो गयी। इसी बीच कैप्टन ढेबर ने सारी जानकारी केंद्रीय उड्डयन मंत्री शिवराज पाटिल को दी।

केंद्रीय उड्डयन मंत्री पाटिल ने दिल्ली वापस होते हुए लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रभारी अग्निहोत्री को जमकर डाट पिलायी और दिल्ली पहुंचने के बाद उनका तबादला गोहाटी हो गया। अग्निहोत्री के तबादले से एयरपोर्ट अथार्टी के अधिकारियों में काफी रोष है। उनका कहना है कि कैप्टन ढेबर प्रधानमंत्री के मित्र होने के कारण अपनी गलतियों को छिपाकर उसका दोष एयरपोर्ट अथार्टी पर मढ़ रहे हैं।

स्वामी-प्रधानमंत्री संपर्क

जनता पार्टी के नेता तथा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इधर प्रधानमंत्री निवास में अपनी काफी घुसपैठ बना ली है। वे अकसर प्रधानमंत्री निवास में देखे जाते हैं। पिछले महीने उन्होंने कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा जनता दल के उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े पर आरोप लगाने के लिए दिल्ली के प्रेस क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन किया। इसके कुछ ही घंटे के बाद वे प्रधानमंत्री निवास में देखे गये। स्वामी इस बात को छिपा भी नहीं रहे हैं। जब दूसरे दिन कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप पत्रकार सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री निवास गये थे, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और बताया कि हिंदूजा बंधु भी वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री निवास में वे किससे मिले या क्या बात हुई, इसका कोई ब्योरा उन्होंने नहीं दिया।

चीन यात्रा के पहले स्वामी प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिले थे। उसके बाद वे अकसर प्रधानमंत्री निवास में देखे जाते हैं। इधर दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को—निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि स्वामी द्वारा लगाये जाने वाले आरोपों को अच्छा कवरेज दिया जाये। बताया जाता है कि यह निर्देश प्रधानमंत्री निवास से जारी किया गया है। लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव गोपी अरोड़ा इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि स्वामी किसी भी समय प्रधानमंत्री को परेशानी में डाल सकते हैं। एक ऐसी स्थिति आ सकती है, जब वे यह कह दें कि उनको सारे दस्तावेज प्रधानमंत्री निवास से दिये गये थे। उस स्थिति में दूरदर्शन और रेडियो क्या उनको ब्लैक-आउट करेगा? लेकिन प्रधानमंत्री निवास में बैठे कुछ लोग गोपी अरोड़ा की बात नहीं सुन रहे हैं।

दूसरी ओर जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर अभी भी जनता दल पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि स्वामी को दल में कोई स्थान देकर उसे काम में लगा दिया जाये, जिससे उसकी बोलती बंद की जा सके। लेकिन दल के दूसरे नेता मानने के लिए तैयार नहीं हैं। स्वामी अब राज्यसभा में अपने आरोपों को उठाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। उनको सत्तारूढ़ दल की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। ■

स्वाद भी पाए. बढ़ता भी जाए... मुन्ना फ़ैरेक्स® के साथ-साथ.

अपने शिशु का वज़न व क़द जाँचिये *	बेटा		बेटी	
	वज़न	क़द	वज़न	क़द
उम्र ३ महीने तक	५.२ कि.ग्रा.	५९.१ सें.मी.	४.९ कि.ग्रा.	५८.४ सें.मी.
उम्र ६ महीने तक	६.७ कि. ग्रा.	६४.७ सें.मी.	६.१ कि.ग्रा.	६३.७ सें.मी.
उम्र ९ महीने तक	७.३ कि.ग्रा.	६८.२ सें.मी.	६.९ कि.ग्रा.	६७.० सें.मी.
उम्र १२ महीने तक	८.४ कि.ग्रा.	७३.९ सें.मी.	७.८ कि.ग्रा.	७२.५ सें.मी.

* इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी किया गया.

भारतीय शिशुओं के लिए यह केवल एक औसत है. अगर आपका डॉक्टर शिशु के विकास से संतुष्ट है तो चिंता की कोई बात नहीं.

रंगीन 'बेबी केअर गाइड' पुस्तिका मुफ़्त मंगाने के लिए लिखिये :
ग्लैक्सो लि. (FPD/ 245),
डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली,
बम्बई-४०० ०२५.

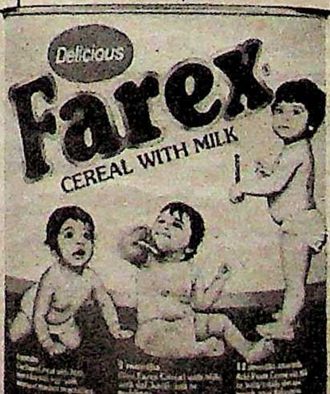

शिशु के चहुमुखी विकास और वृद्धि के लिए उसे पौष्टिकता से भरपूर आहार ''फ़ैरेक्स'' दीजिये.

फ़ैरेक्स®
शिशु बढ़े. फूले-फले...
जब फ़ैरेक्स मिले

CLARION/B/26/244 HIN

बहुत उदास है रात

बुजुर्ग दरबारियों ने जब समवेत स्वर में दिल्ली दरबार को यह समझाया कि 'इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात।' तो बूटा सिंह भड़क उठे—"नही सर, इनसे बगावत की बू आ रही है। इन पर बुलडोजर चला देना चाहिए। ये अपने को समझते क्या हैं? हमारी जूठन पर पलते हैं और हम पर ही गुर्राते है। हम एक बार राजा मांडा (वीपी सिंह) को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इनको उनकी औकात पर ही पहुंचा दिया जाना चाहिए।" दरबार को बूटा सिंह का पंचम में दहाड़ना बहुत अच्छा नही लगा, उन्होंने खड़े होकर दीवार की तरफ मुंह कर लिया। दरबार एक सेकेंड भी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े नही रह पाये, क्योंकि दीवार पर टंगे देश के मानचित्र पर नीचे से पूरा दक्षिण (केरल, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु) गायब था। बूटा सिंह ने जब दरबार के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखीं, तो उन्होंने अपना मेकअप तुरन्त बदल दिया और अपनी पगड़ी से सांत्वना के स्वर निकाल कर उनके करीब आ गये, "सर, आप देश के मानचित्र को देखकर अगर ऐसे परेशान होने लगे, तो राजा मांडा उड़ा देगा कि दरबार नर्वस हो गया है। सर, आप सोचें तो हमने तमिलनाडु में हार कर कुछ भी नहीं गंवाया है। वह हमारे पास कब था! जो चीज थी ही नहीं, उसके जाने का क्या दुख? इस समय तो हमको अपने घर के विद्रोह पर कंट्रोल करना होगा। अगर उसे कंट्रोल न किया गया, तो...।"

बूटा सिंह अपना वाक्य पूरा कर ही रहे थे कि पीछे से अर्जुन सिंह ने अपनी नाक पर आ रहे चश्मे को ठीक करते हुए गुरु गंभीर स्वर में कहा, "महाशय, उसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। अब आप दुश्मन पर नहीं, बल्कि दोस्तों पर पीछे से वार करने लगे हैं।" बूटा सिंह ने अर्जुन सिंह को दरबार में देखकर आपा खो दिया, "बघेल ठाकुर, दरबार में आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? दिल्ली दरबार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा-हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पहले जाकर चुरहट लाटरी से निपटो, वह तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए हथकड़ी लिये खड़ी हुई है।" अर्जुन सिंह ने उसी गुरु गंभीर स्वर में बूटा सिंह का जवाब दिया, "महाशय, मेरे पिताश्री ने भी जेल काटी थी। अगर मैं भी जेल काट लूंगा, तो इसमें नया क्या होगा? हम बघेलों के भाग्य में ही जंगल है। लेकिन महाशय, आपके पुरखों ने तो दिल्ली दरबार का सुख भोगा है। मैं आपको सचेत करने आया हूं कि अब आप कहीं उस सुख से वंचित न हो जायें? आपके दरबार में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है।" बूटा सिंह तो अर्जुन पर खड़े-खड़े क्रोध करते रहे, लेकिन सीताराम केसरी ने उनकी गरदन पकड़ ली, "हमने षड्यंत्र का भंडाफोड़ दिया है। दरबार के खिलाफ तुमने षड्यत्र किया था। मेरा राज्यसभा टिकट कटवाया, क्या यह तुम्हारा षड्यत्र नहीं था? दरबार को मेरे बहुमूल्य परामर्श से वंचित कर दिया। क्या तुमने बूटा सिंह को दरबार से अलग कर देने का षड्यत्र नही रचा? क्या किनारे पर अटके प० कमलापति त्रिपाठी को तुमने दरबार का दुश्मन नही बना दिया? क्या पंजाब में तुम आतंकवाद के नये बीज बो कर नहीं आये? आज हमने तुम्हें पीछे से मारा, तो तुमको इतनी परेशानी हो रही है।" केसरीजी से अपना गला छुड़ाते हुए संयत स्वर में अर्जुन सिंह ने कहा, "वत्स, हमने तुम लोगों को ऐसे मौके और ऐसे समय पर क्षति पहुंचायी, जिससे दरबार को कोई क्षति नही हुई। लेकिन तुमने मुझे ऐसे समय और ऐसी जगह घेर कर मारा कि उससे दरबार को बहुत बड़ी क्षति हुई। इसकी भरपाई अब तुम लोग नहीं कर पाओगे।" अर्जुन सिंह ने नाक पर खिसक आये चश्मे को फिर से नाक पर बिठाया और दरबार से विदा लेने के लिए घूमे, तो उनको पीछे से पी शिवशंकर ने पकड लिया—"क्षत्रिय को क्रोध करना चाहिए बघेल ठाकुर! लेकिन तुम क्रोध नहीं कर रहे हो। यह ठीक नहीं है।" अर्जुन सिंह ने रुककर जवाब दिया, "शिवशंकरजी, क्रोध से मति मारी जाती है। अभी मुझे अपनी मति (बुद्धि) से काफी काम लेना है।" अर्जुन आगे बढ़े, तो शिवशंकर ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, "मुझसे क्यों नाराज हो यार, मैंने दरबार से कहा था कि तमिलनाडु की आंधी ने दरबार का संतुलन बिगाड़ दिया और यह बूटा उन पर हावी हो गया।" अर्जुन सिंह ने फिर गुरु गंभीर वाणी में कहा, "शिवशंकरजी, मैंने तो फैसला आते ही त्यागपत्र देने की बात दिल्ली दरबार से कही थी। लेकिन उन्होंने फौरन मना कर दिया कि ऐसे फैसले तो आया ही करते हैं। अगर ऐसे फैसलों पर इस्तीफे होने लगे, तो एक दिन मुझे भी दरबार छोड़कर भाग खड़ा होना पडेगा। फिर मुझे इस तरह जलील क्यों किया गया?" शिवशंकर ने फुसफुसाकर कहा, "अरे, तुम तो सब जानते ही हो। यह बूटा मचल गया कि मैं अर्जुन सिंह को अपनी तरफ से इस्तीफा देकर अपनी ईमेज बनाने नही दूंगा। पहले उसे ऐसा दिखाऊंगा कि इस्तीफा देने की कोई जरूरत नही। जब वह इस्तीफा न देने की बात करेगा, तो फिर दरबार से उसके इस्तीफे का फरमान जारी करवा दूंगा। इससे उसकी सारी ईमेज चौपट हो जायेगी। वही उसने किया। दरबार आजकल बूटा के चंगुल में है। तुम चक्रव्यूह में फंस गये अर्जुन।" अर्जुन सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा, "अर्जुन चक्रव्यूह से निकलना भी जानता है।" पीछे से शिवशंकर ने फिर बहुत आहिस्ता से पूछा, "क्या मप्र में कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाने की सोच रहे हो। अगर ऐसा है, तो मुझे भी रख लेना। मुझे तो वह एनटीआर अपने आंध्र में घुसने नहीं देगा। मप्र में ही रह कर जिंदगी के बाकी दिन काट लूंगा।" अर्जुन सिंह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दृढ़ता से कहा, "अभी तो यह देखना है कि दरबार मोतीलाल वोरा को विधानसभा में कैसे पहुंचाता है? उसे मैंने (चीनी का) बोरा न उढ़ा दिया, तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह नहीं।"

अर्जुन सिंह दरबार के द्वार से निकल रहे थे कि उधर से दनदनाते हुए गुजरात के जीना भाई दारजी, राजस्थान के हरिदेव जोशी, उड़ीसा की नन्दिनी सत्पथी अपने दल-बल के साथ 'मुख्यमंत्री बदलो' के नारे बुलंद करते हुए प्रवेश करने को थे। अर्जुन सिंह रुक कर मुस्कराये, "मुख्यमंत्री बदल देने से अगर सब कुछ ठीक हो जाये, तो जरूर मुख्यमंत्री बदलो। लेकिन...।" अर्जुन सिंह ने जब अपना वाक्य पूरा नहीं किया, तो जीना भाई दारजी ने पूछ लिया, "लेकिन के बाद क्या है? अर्जुन सिंहजी। बोलते क्यों नहीं। अब तो तुम्हारी बोलती खुल गयी है। इतना संकोच क्यों?" अर्जुन सिंह फिर भी चुप रहे, केवल मुस्करा दिये। जीना भाई ने फिर कहा, "दरबार को बदलने की आवाज बुलंद करना चाहते हो। वह फिलहाल मैं नहीं करने का।" अर्जुन सिंह हल्का-सा मुस्करा कर बुदबुदाये, "दरबार को तो बदलने के लिए मेरा छोटा भाई (वीपी सिंह) ही काफी है। उसमें उसको किसी और की जरूरत नहीं होगी।

दरबार में नारेबाजी शुरू हो गयी, "मुख्यमंत्री बदलो।" किसी बुजुर्ग दरबारी ने बूढ़े स्वर में कहा, "साल बीतते-बीतते तुम लोगों की मुख्यमंत्री बदलने की मुराद जरूर पूरी हो जायेगी।" इसी बीच बुजुर्ग दरबारियों ने समवेत स्वर में दिल्ली दरबार की जगह विद्रोहियों को समझाया, "खंडहर में कुछ दिये हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात।"

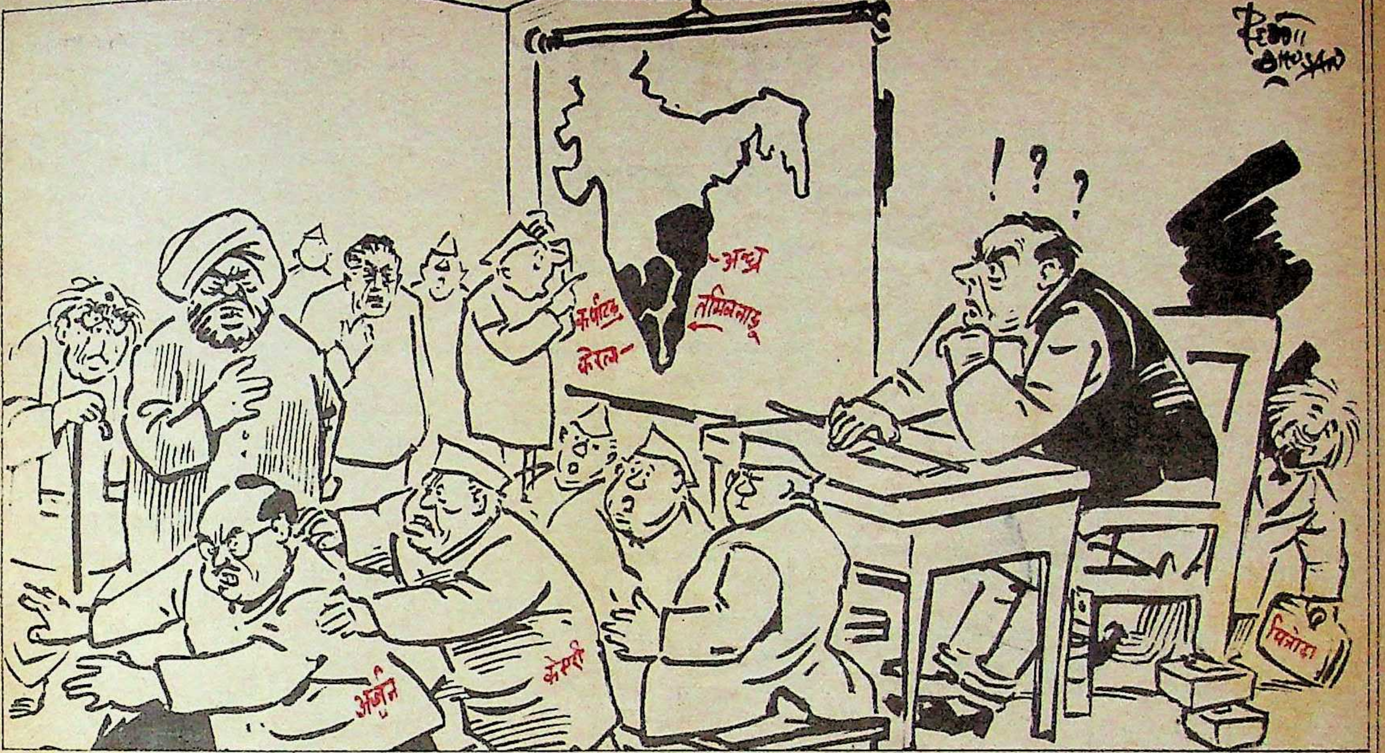

फिलहाल अगर दरबारी बदलने की बात करो, तो काम चलेगा।" दारजी ने अर्जुन सिंह को अंगूठा दिखाते हुए कहा, "आज तुमको ये दरबारी नहीं भा रहे हैं, तो हम लोगों को दरबारी बदलने के लिए उकसा रहे हो। कल तक जब तुम दरबारी थे, तो चाणक्यीय अंदाज में यही समझाते थे कि जब तक समूची वैकल्पिक व्यवस्था पैदा न कर ली जाये, तब तक वर्तमान व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहिए। अराजकता पैदा हो जाती है। मुझे अब अराजकता पैदा नहीं करनी है। केवल मुख्यमंत्री बदलना है। तुम बदले हो, तो दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री क्यों टिके रहें?" अर्जुन सिंह तो मुस्करा कर रह गये। लेकिन तेजी से सीताराम केसरी ने आकर जीना भाई को दबोच लिया, "अर्जुन सिंह भ्रष्टाचार के कारण मुख्यमंत्री पद से गये हैं। दूसरे मुख्यमंत्री उतने भ्रष्ट नहीं हैं। इसलिए उनको निकालने का सवाल पैदा नहीं होता है। पहले अपने मुख्यमंत्रियों को अर्जुन सिंह की तरह भ्रष्ट बनाओ। उसके बाद हम देखेंगे कि उनको निकालना है कि नहीं।" जीना भाई ने केसरीजी को धक्का मार दिया और यह कहते हुए अन्य लोगों के साथ दरबार की ओर बढ़ गये, "अब हम लोगों के पास समय नहीं कि मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा करते फिरें। हमारे लिए निकम्मा मुख्यमंत्री भी भ्रष्ट की ही श्रेणी में आता है।" केसरीजी से छूटे जीना भाई बूटा सिंह की लपेट में आ गये, "जीना भाई, हमने तो आपको एक केन्द्रीय आयोग में कुछ बना रखा है। फिर भी तुम इन विद्रोहियों का झंडा उठाये हुए हो!" जीना भाई ने तपाक से बूटा सिंह को जवाब दे दिया, "जिसका तुम लोगों ने अध्यक्ष बना रखा है, वह भी कोई आयोग है। उसमें पूरी बकवास है। उसे अभी तक केन्द्रीय मंत्री तक का दरजा नहीं मिला। दारजी को कुछ और नहीं दरजा चाहिए।" बूटा सिंह ने जीना भाई के पास आकर धीरे से कहा, "जीना भाई, तुम तो पुराने आदमी हो। ऐसी बेशर्मी से ओहदों की बात करते हो, इससे तुम्हारी इज्जत को बट्टा लग जायेगा।" जीना भाई ने बूटा सिंह का हाथ अपने कंधे से उतार दिया, "बट्टा गया सिलबट्टे में। यहां खुले लेन-देन में हम ही पीछे क्यों रहें? अगर मुझे कुछ नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे अमर सिंह चौधरी को चलने नहीं दूंगा। मैंने उसके गले में पहले घंटी, विश्वास मत प्राप्त करो, बांध दी। अगर इसमें वह सफल भी हो गया, तो क्या हम उसे चैन से बैठने देंगे।" पीछे चुप खड़े हरिदेव जोशी से न रहा गया, "जीना भाई, तुमने अपनी दरजीगीरी काफी चला ली है, अब मुझे भी कुछ बोलने का मौका दो। बूटा सिंह जी, आप अब उस कायस्थकुल भूषण माथुर को बदल रहे हैं कि नहीं।" बूटा सिंह तुरन्त जीना भाई से अलग होकर जोशीजी की तरफ मुखातिब हो गये, "पंडितजी, विचार तो चल रहा है। लेकिन आप तो जानते हैं कि दरबार का लम्बू (अमिताभ बच्चन) काफी वजनी है। जब भी शिवचरण माथुर का वजन कम करने की कोशिश करते हैं, वह लम्बू अपना वजन रख देता है।" जोशीजी ने दुर्वासा ऋषि की भंगिमा चेहरे पर लेकर बूटा सिंह से पूछा, "मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि दरबार में छल-कपट की नीति का अंत कब होगा?" पीछे से खरामा-खरामा टहलते हुए अर्जुन सिंह फिर लौट आये और उन्होंने आहिस्ता से कहा, "जब तक दरबार का पूरा पतन नहीं हो जाता, तब तक पंडितजी..." जोशीजी ने मुंह बिचका लिया, तो मतमताती हुई नन्दिनी सत्पथी बूटा सिंह पर लपक लीं, "हमारे जानकी बाबू (जानकी बल्लभ पटनायक) पर तो अब निर्णय ले लिया जाना चाहिए। क्या हम लोगों को बिहार स्टाइल में कुछ करना होगा?" बूटा सिंह ने नन्दिनीजी की ओर निहारा, "अरे, तुम्हारे बाल तो बिलकुल सफेद हो गये हैं। तुम्हारा भी एक जमाना था नन्दिनी। इस बुढ़ापे में क्यों वापस लौट आयी, इस दरबार में। अरे तुम्हारे तो भजन कीर्तन के दिन आ गये थे।" नन्दिनी सत्पथी बूटा सिंह को कोई करारा जवाब दें कि उसके पहले ही उग्र के कुछ लोगों को वीर बहादुर सिंह ने 'मुख्यमंत्री तिवारी बदलो' की तख्तियां लेकर आगे ढकेल दिया। दरबार में नारेबाजी शुरू हो गयी, "मुख्यमंत्री बदलो।" किसी बुजुर्ग दरबारी ने बूढ़े स्वर में कहा, "साल बीतते-बीतते तुम लोगों की मुख्यमंत्री बदलने की मुराद जरूर पूरी हो जायेगी।" इसी बीच बुजुर्ग दरबारियों ने समवेत स्वर में दिल्ली दरबार की जगह विद्रोहियों को समझाया, "खंडहर में कुछ दिये हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात।"

—दरबारी लाल

देश

१६ जनवरी: तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ भूगर्भशास्त्री एसडी नौटियाल तथा प्रसिद्ध मलयालम फिल्म अभिनेता प्रेम नजीर का निधन।

१७ जनवरी: अखिल भारतीय सिख छात्र के नेता गुरनाम सिह की हत्या। उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश आरएस सरकारिया भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष बने।

१८ जनवरी: कर्नाटक के सार्वजनिक निर्माण मंत्री एचडी देवगौडा द्वारा मंत्री पद छोड़ने का फैसला। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बृहद मिजोरम की मांग से इनकार।

१९ जनवरी: भारत के रमेश कृष्णन द्वारा आस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में शीर्षस्थ खिलाडी तथा गत विजेता मैट्स विलेंडर को पराजय।

२० जनवरी: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा चुरहट लाटरी कांड की निष्पक्ष एजेंसी से जांच का आदेश तथा मुख्यमंत्री अर्जुन सिह से बंगले के खर्च के ब्यौरे की मांग, विपक्ष द्वारा अर्जुन सिह से इस्तीफे की मांग।

२१ जनवरी: तमिलनाडु, नगालैंड और मिजोरम विधानसभाओं के लिए मतदान। बैडमिंटन खिलाडी प्रकाश पादुकोण द्वारा अपने प्रिय खेल से सन्यास लेने का फैसला। एचडी देवगौडा का इस्तीफा मंजूर।

२२ जनवरी: बिहार के राज्यपाल गोविंद नारायण सिह और मप्र के मुख्यमंत्री अर्जुन सिह द्वारा इस्तीफा।

२३ जनवरी: तमिलनाडु में द्रमुक को दो-तिहाई बहुमत। सितारवादक पंडित रविशंकर द्वारा ६९ वर्ष की आयु में लंदन निवासी ३८ वर्षीया सुकन्या राजन से विवाह।

२४ जनवरी: पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके सेन बिहार के नये राज्यपाल नियुक्त। नगालैंड में एससी जमीर की अगुआई में कांग्रेस सरकार बनने का ऐलान। रंगकर्मी सफदर हाशमी को मरणोपरांत डीलिट की डिग्री का सम्मान।

२५ जनवरी: मोतीलाल वोरा पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मराठी फिल्मों की अभिनेत्री ६५ वर्षीय कमल भीवाडकर (रत्नमाला) का निधन।

२६ जनवरी: पाकिस्तान जा रही विशेष रेल दिल्ली अटारी स्पेशल एक्सप्रेस उड़ाने का आतंकवादियों का प्रयास विफल। श्रीनगर बंद के दौरान हिंसा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि ७९ वर्षीय श्यामनारायण पांडे का निधन।

२७ जनवरी: हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित पोंग बांध के बिजलीघर में भीषण आग।

२८ जनवरी: गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्र से राष्ट्रीय वेतन नीति के निर्धारण की मांग। विख्यात पुरातत्वविद ८० वर्षीय डा० एचडी सांकलिया का निधन।

२९ जनवरी: बिहार कांग्रेस का संकट गहराया, पर्यवेक्षकों से वार्ता विफल। पंजाब में १२ खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार।

३० जनवरी: एकीकृत अकालीदल (त) के नेता ज्ञान सिह की हत्या। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायती राजनिकायों के विकेंद्रीकरण हेतु बजट सत्र में विधेयक लाने का ऐलान। वेस्टइंडीज दौरे के लिए दिलीप वेंगसरकर सर्वसम्मति से कप्तान बने।

३१ जनवरी: पाकिस्तान में भारतीय राजदूत शैलेंद्र कुमार सिह नये विदेश सचिव बने।

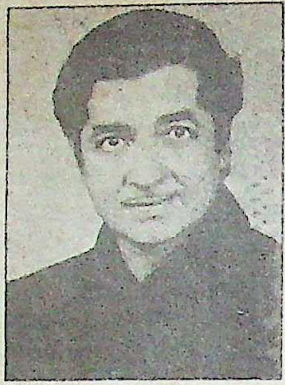
प्रेमनजीर

अर्जुन सिंह

जार्जबुश

पणछेन लामा

विदेश

१६ जनवरी: क्यूबा के तीन हजार सैनिकों ने अंगोला छोड़ा। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में समझौते हेतु उच्चस्तरीय वार्ता का निर्णय।

१७ जनवरी: अमरीकी रक्षा सचिव फ्रैंक कार्लसी द्वारा शस्त्र घटाने की प्रक्रिया पर क्षोभ। राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा लीबिया पर हमला न करने का ऐलान।

१८ जनवरी: पाक में फिलिस्तीनी कार्यालय, फिलिस्तीनी दूतावास बना। ब्रिटेन सरकार द्वारा तमिल नेता विराज मेंडिस को ब्रिटेन छोड़ने का आदेश।

१९ जनवरी: पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा मोरारजी देसाई को निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित करने पर इनकार। अमरीका द्वारा भारत-पाक से संबंध और बेहतर करने का ऐलान।

२० जनवरी: जार्ज बुश ने नये राष्ट्रपति की हैसियत से अमरीका की बागडोर संभाली। पाकिस्तान में परमाणु संयंत्र लगाने की रूस की पेशकश।

२१ जनवरी: अफगानिस्तान में ४५० विद्रोही मारे गये। सोवियत संघ द्वारा पोलैंड से सेना हटाने का ऐलान।

२२ जनवरी: पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सूबे में भारी दल-बदल। प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो द्वारा ११ फरवरी को चीन जाने का फैसला।

२३ जनवरी: सोवियत संघ के एशियाई भूभाग में स्थित ताजिकिस्तान राज्य में भयंकर भूकंप, १८०० मृत। अति यथार्थवादी चित्रकार ८४ वर्षीय सल्वाडोर डाली का निधन।

२४ जनवरी: जापान के योजना मंत्री केन इरादा द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कांफ्रेंस (आईसीसी) द्वारा दक्षिण अफ्रीका जाकर खेलने अथवा प्रशिक्षण देने पर पांच वर्ष का प्रतिबंध।

२५ जनवरी: अमरीका के नये राष्ट्रपति जार्जबुश द्वारा २५-२६ फरवरी को चीन जाने का फैसला।

२६ जनवरी: कुवैत में तेरह सौ भारतीय मजदूरों द्वारा भारतीय मालिकों के खिलाफ हडताल। पश्चिम जर्मनी की एक कंपनी द्वारा परमाणु तकनीक के अवैध निर्यात में पाकिस्तान दूतावास का हाथ होने का भंडाफोड़।

२७ जनवरी: सोवियत संघ के रक्षामंत्री जनरल दिमित्री याजव काबुल पहुंचे। अफगानिस्तान में हालात बिगड़े, फ्रांस और ब्रिटेन के दूतावास बंद।

२८ जनवरी: बांग्लादेश में नगरपालिका चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा और तोड़फोड़। लाहौर में उपचुनाव के दौरान हिंसा।

२९ जनवरी: पाकिस्तान के उपचुनावों में बेनजीर की पार्टी पिछड़ी। तिब्बत के दूसरे वरिष्ठ धार्मिक नेता पणछेन लामा का निधन।

३० जनवरी: १९८६ की दुर्घटना के कारण बंद पडे चरनोबिल परमाणु संयंत्र में कार्य शुरू। सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा क्यूबा जाने का फैसला।

३१ जनवरी: कनाडा का फौजी विमान दुर्घटनाग्रस्त, १८ फौजी मृत। रंगभेद विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष आर्कबिशप टेकर हडलस्टन द्वारा नामीबिया से सोवियत संघ की सेना हटने पर क्षोभ।

शर्मिला ठाकुर की शूटिंग दिल्ली में बारिश के मौसम में हुई।

सभी कलाकारों-गायकों ने निःशुल्क काम किया था। ताजमहल का हवाई दृश्य फिल्माने के लिए एयर चीफ मार्शल दे ला फातेन ने वायुसेना का एक हेलिकाप्टर निःशुल्क मुहैया कराया था। समूचे भारत के दूरदराज खूबसूरत लोकेशनों पर जाकर सुरेश मलिक तथा छायाकार आरएम राव ने शूटिंग कर मात्र डेढ़ महीने में फिल्म पूरी कर दूरदर्शन तथा लोक सचार परिषद को सौंप दिया।

विज्ञापन की दुनिया से एक लंबे अरसे से जुडे सुरेश मलिक तथा कैलाश सुरेंद्रनाथ की पूरी कोशिश थी कि न तो यह प्रचारात्मक डाक्युमेंट्री फिल्म बनने पाये और न ही विज्ञापन फिल्म। इसमें कथ्य के साथ मानवीयता को उभारा जाये। इतने बडे कैनवास को—समूचे भारत को सिर्फ पांच मिनट में समेटना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखलाया। और अगर उन्हे १९८९ के लिए फिर नयी फिल्म का आफर मिला, तो वे उसे और भी प्रभावशाली ढंग से बनायेंगे।

यों इसे देखकर उन प्रांतों के लोगों को शिकायत हो सकती है, जिनकी सांस्कृतिक परपरा काफी समृद्ध है, लेकिन फिल्म में शामिल नहीं किया गया। लोगों को यह भी शिकायत थी कि जब दूसरे प्रांतों की महिलाओं को उनके पारंपरिक वेशभूषा में दिखलाया गया था, तो तनूजा को महाराष्ट्रीय वेशभूषा में क्यों नहीं दिखलाया गया? हेमामालिनी, शर्मिला ठाकुर, शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती तथा जीतेंद्र को ही बतौर स्टार क्यों पेश किया गया?

लेकिन इसके निर्माताओं में एक कैलाश सुरेंद्रनाथ इस विवाद में नही जाना चाहते। उनका कहना है, "यह फिल्म लोगों की मानवीय अनुभूतियों को प्रभावित करने के लिए बनायी गयी है, यह कोई बौद्धिक वक्तव्य नहीं है। अगर इसे देख कर लोग अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कर सकें, तो समझिए हम अपने उद्देश्य में सफल हो गये। बस!"

—बंबई ब्यूरो

अखबारी युद्ध की शुरुआत

बाल ठाकरे

जवाहर लाल दर्डा

ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, त्यों-त्यों नेतागण पैंतरे बदल रहे हैं। कोई अपने क्षेत्र में लोकलुभावन कार्य कर वोटरों का मन जीतने का प्रयास कर रहा है, तो कोई अपना प्रचार करने के लिए अखबार ही निकाल दे रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्यमंत्री जवाहरलाल दर्डा तथा शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद पडे हैं और अपने मुखपत्र के रूप में दर्डा ने १४ जनवरी' ८९ से नागपुर से हिंदी में 'लोकमत समाचार' तथा बाल ठाकरे ने २३ जनवरी' ८९ से मराठी में 'सामना' का प्रकाशन शुरू कर दिया है। दर्डा पहले से ही मराठी दैनिक 'लोकमत' का नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव से प्रकाशन करते रहे हैं।

'लोकमत समाचार' का प्रकाशन स्थानीय अखबारों की सतही छींटाकशी के जिस दौर से शुरू हुआ, उसने सभी को अचंभित कर दिया। संभवत: इस तरह का हादसा इसके पूर्व किसी प्रकाशन के शुभारंभ के समय नहीं हुआ। विदर्भ में सबसे ज्यादा बिकनेवाले 'नवभारत' के प्रधान संपादक ने 'लोकमत समाचार' के प्रकाशन तथा उसकी एक रुपए कीमत की कटु आलोचना करते हुए 'जवाहरलालजी दर्डा के लिए सर्वथा अशोभनीय' शीर्षक से अपने संपादकीय में कहा—'यह मनोवृत्ति विदर्भ के प्रेस पर कुठाराघात है और पूंजीवादी मनोवृत्ति का ज्वलत उदाहरण है। दर्डा जैसे राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति के लिए, जो अकसर गांधीवादी दर्शन और उन्नत विचारधारा के उदगार प्रकट करते रहे हैं, यह शोभनीय नही है।' एक दूसरे हिंदी दैनिक 'राष्ट्रदूत' और नागपुर पत्रिका ने भी 'लोकमत' की खिंचाई की। दरअसल, इसकी शुरुआत खुद मराठी 'लोकमत' ने की। १२ जनवरी' ८९ को 'लोकमत' ने लोकमत समाचार के प्रचार-अभियान में छापा था—'अब तक विदर्भ की हिंदी पत्रकारिता मृतप्राय हो गयी थी। एक तरफ जातिवाद, धर्मांध पत्रकारिता और दूसरी तरफ इतवारी बाजार की दूकानदारी प्रवृत्तिवाली पत्रकारिता— इससे विदर्भ में सुसंस्कृत पत्रकारिता की ऐसी-तैसी हो गयी।' इसके साथ पाठक के सिर का रेखांकन था, जिसमें सिर कों ढक्कन की तरह खोल कर उसमें कुछ अखबार रखे हुए दिखलाये गये थे।

इसका जवाब देते हुए 'राष्ट्रदूत' ने प्रथम पृष्ठ पर 'सवाल पत्रकारिता और इतवारी की अस्मिता की' शीर्षक के अंतर्गत अपने संपादकीय में छापा था—"हाय, शनि की संस्कृति से पत्रकारिता को रसातल में पहुंचानेवाले और नंगे चित्रों से युवा पीढ़ी को चरित्रभ्रष्ट करनेवालों को इतवारी बाजार में कौन-सी दूकानदारी नजर आती है यह बताना जरूरी नहीं है..."

जवाहरलाल दर्डा के ये तीनों पत्र एक तरह से कांग्रेस तथा विशेष रूप से श्री दर्डा के प्रवक्ता का काम करेंगे, लेकिन बाल ठाकरे संपादित 'सामना' पूरी तरह से 'शिवसेना' की वकालत समूचे महाराष्ट्र में करेगा। इसके लिए, संभव है, इस वर्ष के अंत तक वे 'सामना' के संस्करण पुणे, औरंगाबाद तथा मराठवाडा के दूसरे प्रमुख गढ़ों से भी शुरू कर दें। बाल ठाकरे का कहना है, "यह समूचे महाराष्ट्र में हिंदुत्व की आवाज बुलंद करेगा—हिंदुत्व का समर्थन इसकी संपादकीय नीति होगी।"

'सामना' के कार्यकारी संपादक अशोक परब्रिद्री एक तरफ इस बात से इनकार करते हैं कि 'सामना' शिवसेना के भोंपू की तरह काम करेगा, लेकिन यह भी कहते हैं कि संपादकीय और लेखों के माध्यम से यह शिवसेना की नीतियों का प्रसार करेगा। 'सामना' के लिए जारी प्रचार-अभियान में बाल ठाकरे को 'हिंदू हृदय सम्राट' कहा गया। बाल ठाकरे का मानना है कि 'शिवसेना की पहुंच महाराष्ट्र के गांवों-गांवों तक हो चुकी है, ऐसे में हमारा साप्ताहिक 'मार्मिक' अपर्याप्त पड़ता था, 'सामना' इस कमी को पूरा करेगा।'

—बंबई ब्यूरो

मोदी घराने की नयी दौड़

यह सही है कि मोदीनगर का मोदी घराना आपस में लड़ता रहता है, किंतु ऐसा नहीं है कि उनकी लड़ाई ने नये उद्योग स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा को समाप्त कर दिया हो। हाल में ही उन्होंने इटली की ओलीवेटी कंपनी से सौदा कर भारत में कंप्यूटर कंपनी बिठाने का निर्णय ले लिया है। इससे वे भारत के, टाटा के बाद, सबसे बड़े कंप्यूटर निर्माता बन जायेंगे। यही नहीं, विसकोस प्लांट (लसलसे पदार्थों का उद्योग) लगाने की भी उनकी इच्छा है। हालांकि इस उद्योग से संबंधित उनकी पहली योजना सरकार द्वारा अस्वीकृत हो चुकी है। कहा जाता है कि भारत में विसकोस उद्योग के शहंशाह माने जाने वाले बिडला घराने ने ही सरकार से उनकी (मोदी घराने की) योजना अस्वीकृत कराने का खेल खेला है। फिर भी मोदी घराना हारा नहीं है। आज भी वे विसकोस प्लांट लगाने के लिए रास्ते हमवार करने में जुटे हैं।

इससे भी ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली खबर यह है कि मोदी घराना दिल्ली से 'फाइनेंशियल टाइम्स' के प्रकाशन के रास्ते हमवार करने में जुटा है। असल में 'फाइनेंशियल टाइम्स' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाने वाला आर्थिक समाचार-पत्र है, जो फिलहाल लंदन और फ्रैंकफर्ट से प्रकाशित होता है। एक खबर के अनुसार मोदी घराने और पत्र के प्रकाशकों के बीच पत्र का दिल्ली संस्करण प्रकाशित करने का समझौता हो गया है। हालांकि फिलहाल समझौता सरकार के समक्ष नहीं पहुंचा है। वैसे भी सरकार विदेशी प्रकाशकों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती, किंतु चूंकि इस समझौते में एक जबर्दस्त निर्यात प्रस्ताव भी है, इसलिए संभव है, सरकार अनुमति दे दे।

यदि मोदी घराने को स्वीकृति मिल जाती है, तो हिंदुजा भी 'इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून' के भारत से प्रकाशन संबंधित अपने पुराने दबे-पड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दिलवाने के लिए पंक्ति में खड़े हो जायेंगे। इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून एक दैनिक समाचार-पत्र है, जो फिलहाल यूरोप तथा एशिया के कई केंद्रों से प्रकाशित होकर विश्व भर में बिक रहा है। यदि मोदी सफल हुए, तो सरकार को हिंदुजा को भी खुश करना पड़ेगा। नतीजतन शीघ्र ही दो अंतरराष्ट्रीय समाचार-पत्रों का प्रकाशन भारत से शुरू हो जायेगा।

मोदी घराना दिल्ली से 'फाइनेंशियल टाइम्स' के प्रकाशन के रास्ते हमवार करने में जुटा है। असल में 'फाइनेंशियल टाइम्स' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाने वाला आर्थिक समाचार-पत्र है जो फिलहाल लंदन और फ्रैंकफर्ट से प्रकाशित होता है।

फर्नांडीस की चेतावनी

विपक्ष को हाल के तमिलनाडु चुनाव में जनता का सहयोग क्या मिल गया उनके हौसले बुलंद हो गये हैं। फर्नांडीस ने तो केंद्र में गैरकांग्रेसी सरकार बनने का सपना भी देखना शुरू कर दिया है। हाल में उन्होंने कोका कोला और पेप्सी कोला से भारत में कंपनी बिठाने की योजना रद्द करने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि जनता पार्टी के शासनकाल में जार्ज फर्नांडीस ने ही कोका कोला और आइबीएम (इंटरनेशनल बिजनेस मशीस) के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया था। हाल में दोनों कंपनियों को योजना रद्द करने की सूचना देते हुए उन्होंने कहा, "अगली सरकार यानी गैरकांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आते ही विदेशी शीतल पेय कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर देगी, इसलिए उनको भारत आने का खयाल छोड देना चाहिए।"

हो सकता है, फर्नांडीस की यह चेतावनी पेप्सी कोला गंभीरता से ले ले, क्योंकि वह अभी भी भारत आने के लिए पुनर्विचार कर रहा है, किंतु कोका कोला तो इस दौड़ में काफी आगे निकल चुका है। वैसे भी कोका कोला के प्रति भारतीय जनता में काफी सहानुभूति है तथा सरकार को भी उसकी योजना काफी लुभाती हैं। अब देखना यह है कि जार्ज फर्नांडीस की चेतावनी का इन कंपनियों पर खासतौर से कोका कोला पर क्या असर पडता है? फिलहाल नोयडा निर्यात क्षेत्र में कोका कोला कंपनी बिठाने का कंपनी का प्रस्ताव अधर में पडा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी स्वीकृति नहीं दी है।

अमरीकी कंपनियों का भारत-प्रेम

खबर गर्म है कि यदि कोका कोला को भारत में प्रवेश मिल जाता है, तो जनरल मोटर्स कंपनी भी पीछे नहीं रहेगी। जाहिर है, अमरीकी मोटर बनानेवाली कंपनियां बहुत दिनों से भारत में प्रवेश करने की टोह में हैं। इस बार मौका वे हाथ से नहीं जाने देंगी। फिलहाल दो कंपनियां तो भारत में इकाई बिठाकर नये मॉडल की गाड़ियां बनाने का फैसला कर चुकी हैं। उनकी योजना तो यह भी है कि यदि उन्हें अनुमति मिली, तो भारत से ही वे अन्य एशियाई देशों में निर्यात भी करेंगी।

अमरीकी मोटर बनानेवाली कंपनियां बहुत दिनों से भारत में प्रवेश करने की टोह में हैं। इस बार मौका वे हाथ से नहीं जाने देंगी। फिलहाल दो कंपनियां तो भारत में इकाई बिठाकर नये माडल की गाड़ियां बनाने का फैसला कर चुकी हैं

यदि अमरीकी कंपनियों को भारत में प्रवेश मिल जाता है, तो भारतीय कंपनियों के लिए खतरा पैदा हो जायेगा। हालांकि भारतीय गाड़ियां, भारतीय पसंद के इतना अनुकूल हैं कि उनका मुकाबला करना आसान नहीं।

असल में अमरीकी गाडी बनानेवाली कंपनियां जापानी कंपनियों के दबाव से ऊब चुकी हैं, क्योंकि जापानी कंपनियां अपनी गाड़ियों का मात्र निर्यात ही नहीं करतीं, अपितु उन्होंने अमरीका में अपनी इकाइयां भी स्थापित कर ली हैं। नतीजतन अमरीकी कंपनियों का बाजार ठंडा पड़ गया है। इसके अलावा अमरीका में स्थापित जापानी इकाइयां अमरीकी कंपनियों से ज्यादा गाड़ियां बनाती हैं, जिससे अमरीकियों को अपनी क्षमता पर संदेह हो गया है। साथ ही वे तकनीकी क्षेत्र में जापान का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वे अन्यत्र अपनी इकाइयां बिठाने की सोच रहे हैं।

अब यदि अमरीकी कंपनियों को भारत में प्रवेश मिल जाता है, तो भारतीय कंपनियों के लिए खतरा पैदा हो जायेगा। हालांकि भारतीय गाड़ियां, भारतीय पसंद के इतना अनुकूल हैं कि उनका मुकाबला करना आसान नहीं। फिर विदेश की फोर्ड कंपनी तो पहले से भारत में मौजूद है। उसने अपने को बचाये रखने के लिए ट्रैक्टरों का क्षेत्र पकड़ा अन्यथा उसे भागने की तैयारी करनी पड़ती। ऐसी स्थिति में अमरीकी कंपनियों का क्या भविष्य होगा, भलीभांति समझा जा सकता है।

—डा० जय दुबाशी

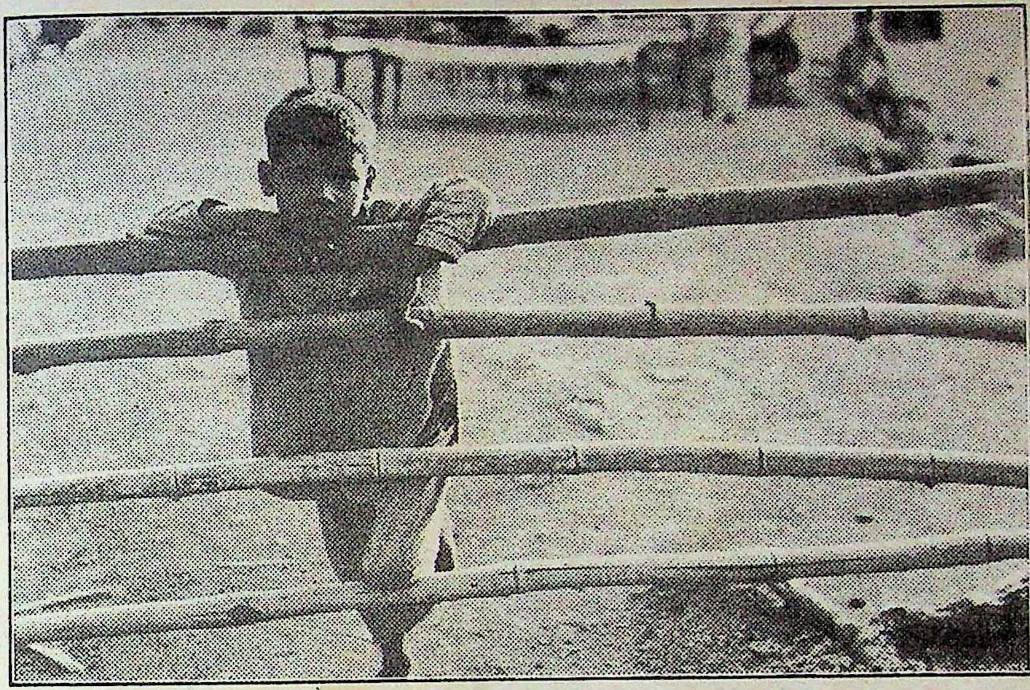

6 साल की उम्र में ही यह बच्चा जीवन की लड़ाई में उतर गया है। छिन गया है इससे इसका बचपन। कारण है हम और आप। क्योंकि हम और आप मिल कर करते हैं उस पैसे की बरबादी जिससे इसके जैसे 10 करोड़ बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया-लिखाया जा सकता है।

दुख की बात तो यह है कि इतना बड़ा सच हमें छूता तक नहीं। कहीं चुभता भी नहीं। क्योंकि हमारे पास कई ज़रूरी चीज़ें हैं सोचने को-करने को। ऐसी फ़ालतू बातों के लिए भला समय कहाँ? हमारी आँखों पर बंधी लापरवाही की पट्टी हमें कुछ देखने नहीं देती।

2000 करोड़ रु० की बरबादी हर साल हो रही है और यह हम सब मिलकर कर रहे हैं।

सड़कों पर, रसोई-घरों में, कारखानों और खेतों में। हर जगह, हर कहीं होती है पेट्रोलियम की बरबादी। क्योंकि ज़्यादा ईंधन खाने वाले पुराने डिज़ाइन के उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं। सवारी की सही देखभाल नहीं होती। और न ही हमारी आदतों और ड्राईविंग के तरीकों में सुधार।

आपके ज़रा से जागरुक प्रयास से इस फ़ज़ूलखर्ची को रोका जा सकता है। लोगों की सोई हुई चेतना को जगाया जा सकता है। बिखरी हुई आवाज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत बरबादी हो चुकी। अब और नहीं। आइए, अब इसके खिलाफ़ आवाज़ उठायें। अपने अखबारों में लिखें। अपनी कॉलोनी, ऑफिस, क्लबों, संस्थाओं—हर तरफ चर्चा करें। काम करने वाले लोगों की सक्रिय टोलियाँ बनायें।

आपकी मदद के बिना कुछ नहीं हो पायेगा। पेट्रोलियम बचाने का संदेश घर-घर तक आपको ही पहुँचाना है।

हम आशा करते हैं कि आप चुप रहने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे।
क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस पन्ने को पलट कर कहेंगे— **"मेरी बला से!"**

इस विषय पर आइए हमसे मिलिए। आपके विचारों का स्वागत है।
पेट्रोलियम कंज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन
P C R A
1008, नई दिल्ली हाऊस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001 फोन: 3310006, 3319066

HTA 5371HIN

क्या महंगाई पर नियंत्रण संभव है ?

वस्तु	मूल्य-वृद्धि
कोयला	३० रुपए प्रति टन।
इस्पात	५० रुपए से ४०० रुपए प्रति टन
चीनी	१५ पैसे प्रति किलोग्राम।
चावल	(राशन की दुकान पर) पांच से ४६ पैसे प्रति किलोग्राम
दूध (दिल्ली)	एक रुपए से डेढ़ रुपए तक प्रति लीटर
पावरोटी (दिल्ली)	२५ पैसे प्रति ४०० ग्राम
ट्रक	१० हजार रुपए या अधिक
यात्री कार	दो हजार आठ सौ रुपए से आठ हजार रुपए प्रति कार

सभी को इस बात की उम्मीद थी कि यह वर्ष (१९८९) विगत कुछ वर्षों की तुलना में बेहतर सिद्ध होगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि चुनाव वर्ष होने के कारण सरकार लोगों पर यह प्रभाव डालना चाहेगी कि वे अतीत से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं, ताकि सत्तारूढ़ दल को जनता का सहयोग मिल सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अधिकांश आशाएं मिथ्या सिद्ध हो चुकी हैं। कोयले, इस्पात, खाद्यान्न, चीनी के मूल्यों के साथ-साथ कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्य सरकार ने पहले से ही बढ़ा दिये हैं। दिल्ली में पावरोटी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। दूध के मूल्य में भी एक रुपए प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। रबर का मूल्य भी कुछ हजार रुपए प्रति टन की दर से बढ़ा है। ट्रकों तथा कारों के मूल्य में भी कई हजार रुपए की वृद्धि हुई है।

हालांकि यह सब बजट-पूर्व हुआ है। किंतु फिर भी यह उम्मीद है कि इस बार का बजट उतना बुरा न होगा, जितना गत कुछ वर्षों में रहा है। वित्तमंत्री यह जानते हैं कि चुनाव-पूर्व बजट में करों अथवा शुल्कों में वृद्धि नहीं की जा सकती। हालांकि चुनाव वर्ष में बजट पूर्व हुई वृद्धि को देखकर लोगों ने नर्म बजट की उम्मीद भी छोड़ दी है, क्योंकि यदि सरकार मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वास्तव में उत्सुक होती, तो कोयले, इस्पात, खाद्यान्न एवं चीनी जैसी वस्तुओं में मूल्य-वृद्धि नहीं होती।

यहां यह जान लेना जरूरी है कि पहले से ही बढ़ गये इन मूल्यों का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव हो सकता है (कृपया बाक्स देखें) ? सर्वप्रथम दिल्ली के ही नागरिक का उदाहरण लिया जाये। उसे एक लीटर दूध के लिए एक रुपए से डेढ़ रुपए तक अतिरिक्त देने होंगे। यानी दो लीटर दूध का मासिक व्यय ६० रुपए से लेकर ९० रुपए तक बढ़ेगा। ४०० ग्राम पावरोटी के लिए उसे २५ पैसे अधिक भुगतान करने होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त भार की एक पावरोटी का प्रतिदिन उपभोग करनेवाले को प्रतिमाह ७ रुपए ५० पैसे अधिक व्यय करने होंगे। संयुक्त रूप से मात्र इन दोनों मदों में व्यय ६७ रुपए ५० पैसे से लेकर ९७ रुपए ५० पैसे तक बढ़ जायेगा। ३०० रुपए प्रतिमाह की आय वाले किसी परिवार के लिए इस वृद्धि का मतलब हुआ सवा दो से सवा तीन (२.२५-३.२५) प्रतिशत की वृद्धि। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसका राष्ट्र के समस्त उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। देश के लगभग १६ करोड़ परिवारों के लगभग ४० प्रतिशत लोग कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हें अब कोयले के मूल्य में प्रति टन ३० रुपए की दर से हुई वृद्धि के कारण अपने प्रयोग हेतु क्रय किये जाने वाले कोयले के लिए कम से कम १० रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे।

चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम १५ पैसे बढ़ाया गया है। इससे चीनी उपभोक्ता के व्यय में प्रति पांच किलो पर ७५ पैसे प्रतिमाह की वृद्धि होगी। चीनी की मूल्य-वृद्धि के कारण गुड़ का मूल्य भी चढ़ेगा। इस तरह चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करनेवाले भी मूल्य-वृद्धि की मार से अछूते नहीं बचेंगे। सरकारी सस्ते गल्ले (राशन) की दुकान पर मिलने वाले मोटे चावल का मूल्य पांच पैसे प्रति किलोग्राम, महीन चावल का मूल्य ४० पैसे प्रति किलोग्राम तथा अतिमहीन चावल का मूल्य ४६ पैसे प्रतिकिलो बढ़ा है। शहरों के राशन कार्डधारी उपभोक्ता के लिए प्रति किलोग्राम अतिरिक्त व्यय अब औसतन २० पैसे के लगभग पड़ेगा। इसका अर्थ होगा प्रति परिवार प्रतिमाह प्रति २५ किलो पर पांच रुपए का अतिरिक्त व्यय।

कुछ ऐसी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। जैसे इस्पात के मूल्य में प्रतिटन ५० रुपए से ४०० रुपए तक वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप दो पहिया वाले

वाहनों एवं अच्छे किस्म के इस्पात से निर्मित होनेवाली अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होनी ही है। ट्रकों के मूल्य में १० हजार रुपए तक की वृद्धि पहले ही हो चुकी है। उत्पादकों का कहना है कि नये इस्पात मूल्यों के चलते उन्हें इस्पात निर्मित वस्तुओं का मूल्य और बढ़ाना पड़ेगा।

मात्र कोयले के मूल्य में वृद्धि से ही ताप-विद्युत का मूल्य कम से कम दो पैसे प्रति यूनिट बढ़ जायेगा। यह वृद्धि वास्तव में अन्य मूल्यों में वृद्धि के कारण और अधिक हो जायेगी। इसके परिणाम स्वरूप एक परिवार के विद्युत बिल में प्रतिमाह २५ रुपए से ५० रुपए के बीच वृद्धि होगी। यही नहीं, विद्युत के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते सीमेंट उद्योग को भी सीमेंट का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। परिणामस्वरूप गृहनिर्माण १५ प्रतिशत अधिक मंहगा होगा तथा मकान, दुकान आदि के किराये बढ़ जायेंगे।

सरकार क्या करे ? : इस्पात, कोयला, विद्युत तथा सड़क एवं रेल परिवहन आदि सभी उद्योगों के निवेश हैं। इन सबके मूल्यों में वृद्धि के कारण सभी औद्योगिक उत्पाद मंहगे हो जायेंगे। यह मूल्य-वृद्धि खाद्यान्न, चीनी, पावरोटी तथा दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं के बढ़े मूल्यों के कारण और प्रोत्साहित होगी। नतीजतन कारखानों के मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। इस तरह मजदूरी तथा वेतन पर उद्योग का व्यय बढ़ेगा। यह सब क्रम से सामान्य उपभोक्ता को ही प्रभावित करेगा।

जाहिर है, सामान्य व्यक्ति
बजट पेश होने से पहले मूल्यों में वृद्धि से इतना चिंतित हो चुका होगा
कि बजट में दी गयी रियायतें उसके लिए
काफी सुखदायी होंगी और वह बजट की ओर आकर्षित होगा,
जिसका फायदा सरकार को मिल सकेगा।

अब यह जानना जरूरी है कि चुनावी वर्ष में उपभोक्ता को मूल्य-वृद्धि के बोझ से क्यों दबाया गया ? ऐसा तो नहीं कि न चाहते हुए भी मूल्यों में वृद्धि करना राजीव सरकार की मजबूरी हो गयी हो ? क्योंकि जहां एक ओर मूल्यों में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर साड़ियों, धोतियों, बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तथा रोजगार जुटाने के भी सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए एक ही समय में सरकार दो जुदा-जुदा रास्ते तो अपना नहीं सकती। क्योंकि जहां पहले रास्ते से जनता पर बोझ डाला जा रहा है, वहीं दूसरा रास्ता मतदाता को फुसलाने का है। इसलिए यह बात साफ हो जाती है कि मूल्यों में वृद्धि सरकार की नीति नहीं, अपितु उसकी मजबूरी है। क्योंकि किसी तरह भी भारी मात्रा में मुद्रा उगाहने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादनों में मूल्य-वृद्धि होना स्वाभाविक है। किंतु यदि सरकार थोड़ा सतर्क हो जाये, तो मूल्य-वृद्धि से उसको पहुंचने वाला नुकसान घट सकता है। इसके लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा, जिससे जो मूल्य-वृद्धि होना है, बजट से पूर्व हो जाये। ऐसा होने से क्षति दो तरह से कम हो जायेगी। एक तो यह कि बजट के तत्काल बाद एक ही समय में होने वाली मूल्य-वृद्धि का कष्ट उठाने से मतदाता बच जायेगा, क्योंकि जब मूल्यों में वृद्धि धीरे-धीरे होगी, तो उसकी अनुभूति कटु नहीं होगी और मतदाता सरकार के खिलाफ नहीं होगा। दूसरे, बजट से पहले ही मुद्रा उगाह लिए जाने पर चुनाव पूर्व पेश होने वाले बजट में यदि नये करों या शुल्कों का कोई भारी बोझ नहीं लादा गया, तो सरकारी प्रचार को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में दूरदर्शन बार-बार यह दोहरा सकता है कि बजट आम आदमी (सामान्य-आदमी) के हित का है। जाहिर है, सामान्य व्यक्ति बजट पेश होने से पहले मूल्यों में वृद्धि से इतना चिंतित हो चुका होगा कि बजट में दी गयी रियायतें उसके लिए काफी सुखदायी होंगी और वह बजट की ओर आकर्षित होगा, जिसका फायदा सरकार को मिल सकेगा।

—कुमारेश चक्रवर्ती

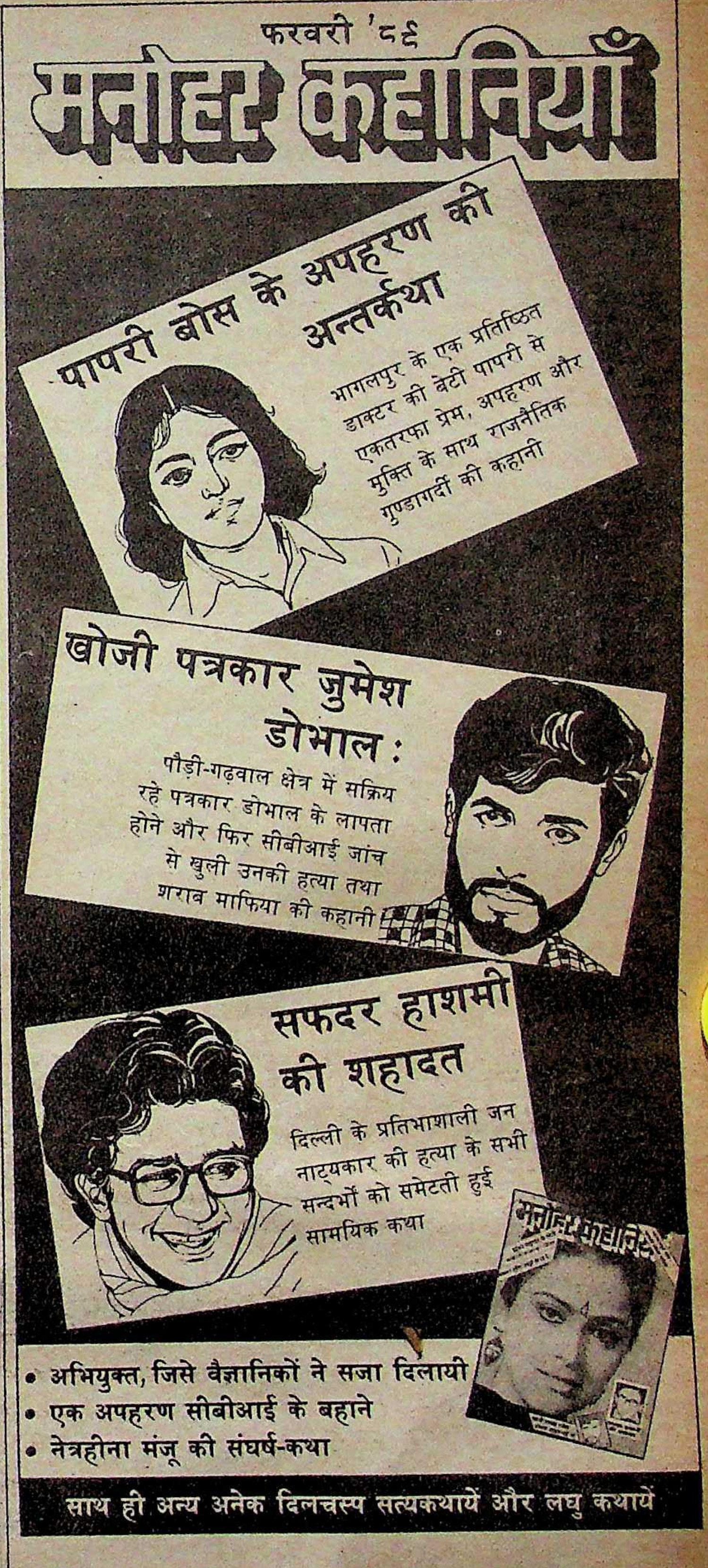

फरवरी '८९
मनोहर कहानियाँ

पापरी बोस के अपहरण की अन्तर्कथा
भागलपुर के एक प्रतिष्ठित डाक्टर की बेटी पापरी से एकतरफा प्रेम, अपहरण और मुक्ति के साथ राजनैतिक गुण्डागर्दी की कहानी

खोजी पत्रकार उमेश डोभाल :
पौड़ी-गढ़वाल क्षेत्र में सक्रिय रहे पत्रकार डोभाल के लापता होने और फिर सीबीआई जांच से खुली उनकी हत्या तथा शराब माफिया की कहानी

सफदर हाशमी की शहादत
दिल्ली के प्रतिभाशाली जन नाट्यकार की हत्या के सभी सन्दर्भों को समेटती हुई सामयिक कथा

- अभियुक्त, जिसे वैज्ञानिकों ने सजा दिलायी
- एक अपहरण सीबीआई के बहाने
- नेत्रहीना मंजू की संघर्ष-कथा

साथ ही अन्य अनेक दिलचस्प सत्यकथायें और लघु कथायें

कंप्यूटर ऐसा भी

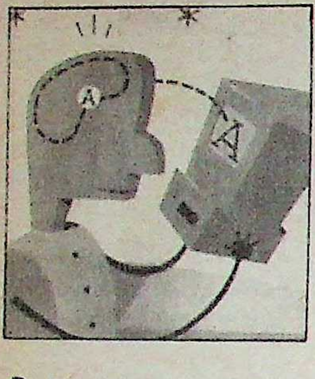

चिकित्सा को अत्यधिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस करने की विश्वव्यापी मुहिम में पश्चिमी देश इतना आगे चले गये हैं कि कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जिस उपकरण या तकनीक की सूचना दी जा रही है, वह सच नहीं, अपितु संभावित वैज्ञानिक चमत्कारों पर आधारित आश्चर्य में डालने वाली किसी काल्पनिक फिल्म का दृश्य है। 'ब्रेन रेसपास इटरफेस' नामक उपकरण भी वैज्ञानिक कल्पना मात्र ही लगता है, जबकि सचाई यह है कि इस उपकरण का प्रयोग शुरू हो चुका है और लकवे के शिकार कई मरीज इससे लाभान्वित भी हुए हैं। असल में 'ब्रेन रेसपास इटरफेस' उन मरीजों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जो लकवे का शिकार होने के कारण बोल नहीं पाते। ऐसी स्थिति में रोगियों का कष्ट जान पाना असभव हो जाता है, जिससे सही समय पर उन्हें सही दवा नहीं मिल पाती और मर्ज दिन-पर-दिन जानलेवा होता जाता है। ऐसे मरीजों को ध्यान में रखकर ही सैन फ्रैंसिस्को स्मिथ केटेलवेल आई रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाक्टर एरिक इ सूटर ने अपनी टीम के सहयोग से एक ऐसा कंप्यूटर डिजाइन किया, जिसके माध्यम से वे मरीज, जिनकी बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है परंतु देख सकते हैं, अपने शारीरिक कष्ट की जानकारी डाक्टर को दे सकते हैं।

'ब्रेन रेसपास इंटरफेस' में दो एलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क से जोड़ दिया जाता है और एलेक्ट्रोड का तार के जरिए कंप्यूटर से सपर्क बना दिया जाता है। इस उपकरण का दूसरा भाग कंप्यूटर स्क्रीन की तरह होता है जिसकी विशिष्टता यह है कि उसमें ६४ मिमोरी डिब्बे होते हैं, जिनमें अंग्रेजी के सभी अक्षर, नंबर तथा आमतौर से बोले जानेवाले शब्द सुरक्षित होते है। मरीज अपने कष्ट की सूचना देने के लिए स्क्रीन की ओर देखता है और मन ही मन अक्षरों का संयोजन कर अपने कष्टों का वाक्य बनाता है। स्क्रीन के सामने मौजूद चिकित्सक मरीज के शरीर में हो रहे बदलाव से अवगत हो जाता है तथा उसके अनुसार दवा या शल्य चिकित्सा की व्यवस्था करता है। इंस्टीट्यूट के सूत्रों का कहना है कि शीघ्र ही यह उपकरण बड़े पैमाने पर बनाया जायेगा, ताकि विश्वभर के मरीजों को इससे फायदा पहुंच सके।

जेनरेटर युक्त घड़ियां

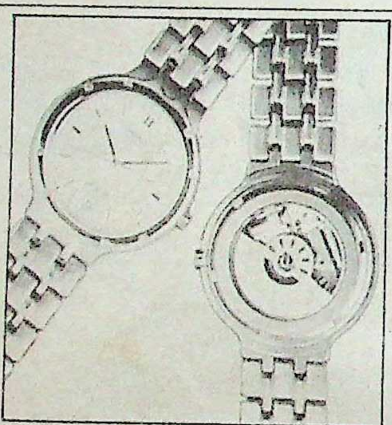

विश्वभर में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, उससे घड़ियों की दुनिया भी अछूती नहीं है। तरह-तरह के माडलों तथा आकर्षक डायलों के कारण तो घड़ियों का बाजार बढ़ा ही, साथ में बदलती मशीनी तकनीक ने भी घड़ियों के बाजार को बढ़त का रुख बनाये रखने में मदद की। स्थिति यह है कि बैटरी से चलनेवाली क्वार्ट्ज घडियो का निर्माण करना या उनका इस्तेमाल करना पिछड़ेपन या भौंडेपन की निशानी बन गया है।

किंतु क्वार्ट्ज घड़ियों का क्रेज खतम करने के लिए नयी तकनीक से बनी घड़ियों ने यूरोप के बाजारों में जगह बनानी शुरू कर दी है। अब सीको कंपनी ने ऐसी घड़ी बना दी है, जो बिना बैटरी लगाये ही चलती है। जाहिर है, अब बैटरी की झंझट में कोई नहीं पड़ेगा और सीको द्वारा बनायी गयी बैटरी-विहीन घड़ियों का युग चल पड़ेगा। हालांकि कंपनी का यह प्रयोग फिलहाल कलाई पर बाधने की घड़ियों में ही सफल हुआ है।

सीको द्वारा बनायी गयी इस बैटरी-विहीन घड़ी में विश्व का सबसे छोटा जनरेटर लगाया गया है जो कलाई की हरकत से ऊर्जा एकत्र करता है, जिसकी सहायता से घडी की सुइया चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कलाई हरकत में न हो, तो घडी बंद हो जायेगी। २४ घंटे में न्यूनतम एक घंटे मात्र की हरकत से जेनरेटर में इतनी ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है कि घडी २४ घंटे से ज्यादा चल सकती है। फिलहाल यह घड़ी इग्लैंड और अमरीका में उपलब्ध है तथा इन्होंने इन देशों में क्वार्ट्ज घड़ियों का बाजार ठंडा कर दिया है।

■

बधिरों के लिए खुशखबरी

१९८८ में एक विशिष्ट चिकित्सक दल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया कि प्रत्येक दस में से एक व्यक्ति को किसी-न-किसी रूप में बधिरता का रोग होता है। इसी सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि ६५ वर्ष की आयु के बाद आंशिक बधिरता एक आम बात हो जाती है और प्रत्येक चार में से एक व्यक्ति इस कठिनाई का शिकार होता है। इस विश्वव्यापी सर्वेक्षण के पश्चात मिलनेवाले आंकड़ों ने 'हियरिंग एड' निर्माताओं के हौसले बढ़ा दिये। नतीजतन तरह-तरह के 'हियरिंग एड' डिजाइन किये जाने लगे और बाजार में आने लगे। किंतु उन सब में एक कमी यह है कि वे जरूरत से ज्यादा भारी होने के कारण या कान की बनावट के आधार पर न बने होने के कारण प्रयोग करनेवालों को कष्ट ज्यादा पहुंचाते हैं। आंशिक बधिर व्यक्तियों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए साइमेन कपनी ने इनसिटा एएसपी नामक एक ऐसा 'हियरिंग एड' उपकरण बनाया है जो कान की बनावट में पूरी तरह से बैठ जाता है तथा हल्का भी इतना होता है कि इस्तेमाल करनेवाले को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। साथ ही इनसिटा एएसपी में लगे एंप्लीफायर इतने संवेदनशील होते हैं कि मामूली-सी आवाज को साफ करके इस्तेमाल करनेवाले तक पहुंचाना उसके लिए बडी मामूली-सी बात है। इस उपकरण का वायरलैस ट्रांसमीटर क्रेडिट कार्ड के बराबर तथा उसी आकार का होता है जिसे जेब में रखना भी मुश्किल नहीं। इनसिटा एएसपी यूरोपीय देशों में उपलब्ध है तथा शीघ्र ही इसका निर्यात भी शुरू होनेवाला है।

—संयोजन : तारिक खान

"हमारे गाँव को सुरक्षा की छाँव"

"जी हाँ ! पशु बीमा अब एक आम बात है – और एक परम आवश्यकता ! चाहे बीमारी हो या प्रकृति का प्रकोप – आग लगे या बाढ़ का जोर – साँप काटे या कोई अन्य दुर्घटना ! पशुक्षति का बीमा अब एक सामान्य सुविधा है। भला हो बीमा कम्पनी वालों का जो अब हम अपने पशुओं का भी बीमा करा सकते हैं – और हमें शहर भी नहीं जाना पड़ता - ओरिएण्टल इंश्योरेंस अपना प्रतिनिधि हमारे गाँव जो भेजती है !!

जब इतनी सुरक्षा हो तो हम बीमा क्यों न कराएं? थोड़ा-सा ही तो प्रीमियम देना पड़ता है !"

ओरिएण्टल इंश्योरेंस अपने ग्रामीण भाईयों के लिए अनेक बीमा योजनाएं चला रही है। जैसे कृषि पम्प सेट बीमा, मुर्गी पालन, मधु मक्खी पालन, रेशम कीड़ा पालन बीमा योजनाएं। जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का बीमा, ग्रामीण दुर्घटना बीमा, एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना इत्यादि।

विस्तृत जानकारी के लिए हमारे किसी भी कार्यालय से, अपनी सुविधानुसार सम्पर्क करें।

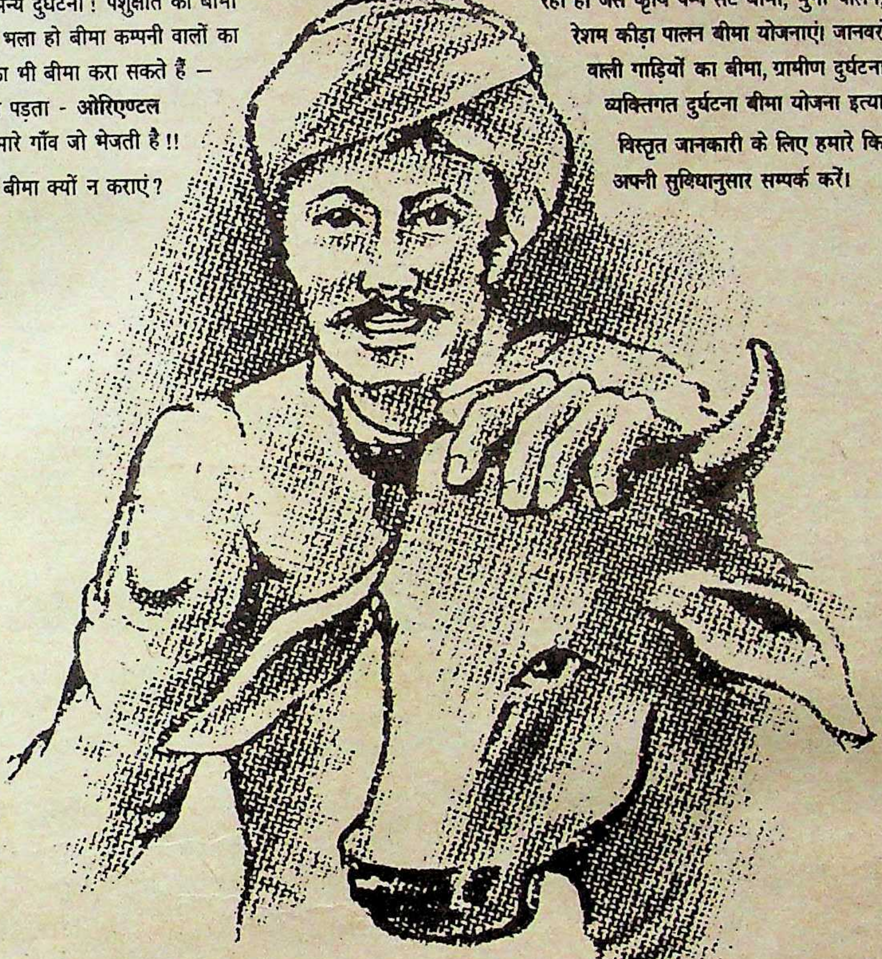

बीमा	**वार्षिक प्रीमियम दर**	
भैंस/गाय	आई.आर.डी.पी. 2 रुपये 25 पैसे	(अन्य) 4.00 रुपये
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	12 रुपये प्रति व्यक्ति	बीमित राशि 15,000 रुपये
ग्रामीण दुर्घटना बीमा	5 रुपये प्रति व्यक्ति	बीमित राशि 6,000 रुपये
खेती-बाड़ी पम्प सेट		
(i) बिजली से चलने वाला	50 से 190 रुपये (हार्स पावर के अनुसार)	
(ii) डीज़ल से चलने वाला	70 से 230 रुपये (हार्स पावर के अनुसार)	
अण्डे देने वाली मुर्गी	आई.आर.डी.पी. 80 पैसे प्रति चूज़ा (1 दिन से 72 हफ़्ते तक)	(अन्य) 1.20 से 1.50 रूपये प्रति चूज़ा (उम्र के मुताबिक)
ब्रायलर	25 पैसे प्रति चूज़ा (1 दिन से 8 हफ़्ते तक)	

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
(भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक कम्पनी)
ओरिएण्टल हाउस, ए- 25/27, आसफ़ अली रोड, नई दिल्ली- 110 002.

जवाहरलाल नेहरू जन्मशती
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

Advtg. Integrated/OIC/189

विसंगतियों का कुंभ

एक अनुभव मेरी आंखों के आगे है, एक उनके पीछे। जिस वक्त बाध की ऊंचाई से रात का दृश्य देखती हू, जगमग रोशनी का अपरपार प्रसार, रंग-बिरंगे पंडाल, भव्य प्रतिमाएं, चित्र-विचित्र अपार! तत्व ज्ञान मण्डप से उठते मंत्रोच्चार तनिक आगे जाकर गंगा की आरती में घुलमिल जाते हैं और जल्द ही किसी कोने से अनूप जलोटा के व्यावसायिक भक्ति-रस में खो जाते हैं। मैं चाहती हूं कुछ दिन के लिए मुझे विसंगति और विषमता दिखनी बंद हो जाये, मैं नयी आंखें पाना चाहती हू। एक जगह प्रवचन हो रहा है। मैं भी बैठ जाती हू। विषय है वैराग्य। स्वामीजी कह रहे हैं 'मनुष्य-जीवन सौभाग्य से मिला, इसे विषयों से दूषित करना उचित नहीं। वैराग्य मनुष्य का भूषण और पोषण है। वैराग्य कैसे आता है। विवेक से। विवेक के लिए क्या करना होगा? सत्संग।'

कटोरी देवी अपने थैले में से एक अमरूद निकालती है "यह देखो, अगर मैं इस अमरूद को काटू, तो इसके बराबर हिस्से करूगी, सबको बराबर-बराबर दूगी, पर मेरी बहू काटेगी, तो छोटा हिस्सा मुझे देगी।"

इसके बाद स्वामीजी सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालते हैं। सभी भक्त स्त्रियां हैं, सास की उम्र वाली स्त्रियां। मेरी भेगी आंख फिर सक्रिय हो जाती है। ये बुजुर्ग स्त्रियां कितने प्रेम और भक्ति-भाव से वैराग्य चर्चा सुन रही हैं। क्या ये अपने परिवार में एक प्रतिशत भी तटस्थता का पालन कर सकेंगी। वापस जाकर ये ज्यों की त्यों बेटों और बहुओं का जीना मुहाल करेंगी, बात-बात में अपना रक्तचाप तेज करेंगी, जिह्वा पर स्वाद और विवाद का नियंत्रण खो बैठेंगी और अपने अतीत के गौरव-गान से परिवारों को वर्तमान संकट में डालेंगी।

स्वामीजी समझा रहे हैं 'सांसारिकता में लिप्त मन को ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं किया जा सकता, न ही इस तरह वैराग्य का प्रादुर्भाव हो सकता है। विषय मन को भटकाते हैं। सत्संग विषयों से आपकी रक्षा करता है। इसके लिए गुरु का आशीर्वाद और सत्संग चाहिए। गुरु ही ब्रह्म है।'

काश इन गूढ़ बातों को स्वामीजी मूर्त बनाकर प्रस्तुत करें, मैं सोचती हू। प्रवचन श्रोताओं के सिर के ऊपर से जा रहा है। स्वामीजी को इसका एहसास है। वे शीघ्र प्रवचन समाप्त करते हैं। मैं उनके मुख पर नजर डालती हू, संभवतः वहां वह असंतोष हो जो अपनी बात न समझा सकने पर वक्ता के मुख पर होता है। वहां संतोष-असंतोष से परे चर्बी की अनेक पर्तें हैं, भगवे रंग की भव्यता है, शिष्य-मंडली का घेरा है, भक्तिनों के मूढ़ नमन हैं, माइक है, टेपरिकार्डर है, फोटोग्राफर हैं।

मैं पंडाल के बाहर कटोरी देवी से बातचीत करने लगती हू।

कटोरी देवी कुछ नाराज लगती हैं। मैं वजह पूछती हू। लड़का यहीं प्रयाग में रहता है। तीन दिन से मिलने नहीं आया। इतनी ठंड पड़ रही है। उसने यह नहीं सोचा कि चलकर मां को एक रजाई और दे आऊं। बूढ़ी हड्डी है, ठंड ज्यादा लगती है। वह बुरा नहीं। वह बहुत कमीनी है, उसके सिखाये में रहता है। उससे दबता है।

"क्या कमीनापन है बहू में?" मैं पूछती हू।

"एक हो तो बताऊं? मुझसे चिढ़ती है। मेरे दूध में पानी मिलाती है, मेरी धोती मैल में धुलवाती है। पहले अपने कपड़े धुलवाती है, बाद में मेरे। मेरे कमरे में झाड़ू नहीं लगवाती। मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाती। मेरे पैर नहीं दबाती। मुझसे बात नहीं करती। अपनी सहेलियां आयें, तो घंटों खुसुर-फुसुर करती है।"

—ममता कालिया

मैं उनके माथे पर बिंदी देखकर पूछती हूं, "आपके पति भी आपके साथ आये हैं?"

"वे क्या आयेंगे? उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं। आराम से घर बैठे टीवी देख रहे होंगे।"

"उनके साथ बहू कमीनगी नहीं करती?"

"उन्होंने ही तो सिर चढ़ाया है। कभी नहीं टोकते। "तुम क्या करती हो?" "टीचर हूं?"

"सब कुछ पढ़ाती हो आप लोग, यह नहीं पढ़ातीं कि अपने बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए? क्या सिखाती हो लड़कियों को? यही कि बीए, एमए पढ़ लिखकर अपने को मेमसाहब समझो। आदमी को अपने इशारे पर नचाओ।"

कटोरी देवी अपने थैले में से एक अमरूद निकालती हैं "यह देखो, अगर मैं इस अमरूद को काटू, तो इसके बराबर हिस्से करूगी, सबको बराबर-बराबर दूगी, पर मेरी बहू काटेगी, तो सबसे छोटा हिस्सा मुझे देगी। यही सीख देती हो स्कूलों में?"

"आपके बेटी है?" मैं पूछती हू।

वह तुरंत मेरा आशय समझ जाती हैं।

"नहीं है, लेकिन होती तो मैं उसे सोने जैसी बनाती, ठीकरे जैसी नहीं। मैंने गिरस्ती उसके हाथ थमा दी कि चार दिन सुख से जीऊंगी। उसने मेरा बुढ़ापा बिगाड़ दिया।"

कटोरी देवी की कर्कश आवाज और मुद्रा के बावजूद मन भीग आया। सत्तर की उम्र की टूटन सत्रह की उम्र की टूटन से ज्यादा निरुपाय लगती है। कहां-कहां चोट खा जाता है मन जीवन की शाम में। इसकी पीड़ा न पति समझ रहा है न पुत्र। छोटी-छोटी तकलीफें हैं, तंगियां हैं, तिलमिलाहटें हैं। इन्हें दूर करना मुश्किल भी नहीं, फिर भी ये एक असंतुष्ट जीवन जी रही हैं।

मैं वहां से वापस होती हुई एक और शिविर में चली जाती हूं। यहां पुरुषों की भीड़ है। स्त्रियां महज चार छह हैं। सब खड़े होकर प्रवचन सुन रहे हैं। स्वामीजी हिंदू धर्म की व्यापकता पर बोल रहे हैं। "हिंदू धर्म कभी भेदभाव की बात नहीं करता। आप शिव की उपासना करें या विष्णु की, राम की या कृष्ण की, साकार की या निराकार की, हिंदू धर्म में सबका सम्मान है। अनपढ़ से अनपढ़ मनुष्य भी हिंदू धर्म की महानता समझ सकता है। जब संसार के सारे धर्म लुप्त हो जायेंगे, तब भी हिंदू धर्म शेष रहेगा।"

पंडाल के बाहर बड़े से बैनर पर लिखा है सर्वधर्म समवाय। मैं अभी प्रवचन और प्रचार के बीच तालमेल बैठा ही रही हू, कि एक बुजुर्ग पास आ जाते हैं।

"बड़ा सुंदर प्रवचन है।" वे कहते हैं।

"जी, लेकिन यह विशेषता सभी धर्मों में है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं।"

वे भड़क जाते हैं। "बिना सोच-विचार के निष्कर्ष नहीं बनाने चाहिए। आपने वेद पढ़े हैं? उपनिषद पढ़े हैं। नहीं एक रामचरित मानस पढ़ा है बस। टीवी पर रामायण देख ली है। हिंदू होने का अर्थ भी नहीं पता है और हिंदू हैं..."

मैं वहां से चल देती हू। साथ के परिचित उनके बारे में बताते हैं, अवकाशप्राप्त बीमा निगम के अधिकारी हैं। पिछले साल अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने एक विजातीय लड़की से विवाह करने का इरादा जाहिर किया था। लड़के ने सिविल मैरिज कर ली, वह खुश है, ये नाराज हैं।

मैं सोच रही हूं, अपनी विसंगतियों के संदर्भ में यह महाकुंभ लोगों के लिए महाशरण है। नहीं? ■

कॉयरफ्लेक्स-अनुभव...
हर कोयरफ़्लेक्स मैट्रेस पर लगा विशेष गारन्टी कार्ड अवश्य देखलें तथा लेबल के हस्ताक्षरों से इस कार्ड के हस्ताक्षर मिला लें।
Guarantee Card
11 57634 F 127 0394
COIRFLEX
Authorised Signatures
Rest assured .. for years

एक नई हलचल, एक नया अंदाज।

सम्भवतः दुनिया में आराम का सबसे सुखद एहसास। कोयरफ़्लेक्स के गद्दे जिनमें नारियल के रेशों को प्राकृतिक लेटैक्स रबर द्वारा स्प्रे विधि से सुगठित किया जाता है।

सादे, अथवा फूलों वाले चित्ताकर्षक डिज़ाइनों एवं मखमली 'क्विल्टिंग' से सजे। जिन्हें उत्कृष्ट बनाने में इनके निर्माताओं का वर्षों का अनुभव कार्यशील है। और साथ है उनका बेजोड़ तकनीकी-ज्ञान जो आपको एक अनूठे आराम का विश्वास दिलाता है।

ग्रीष्म ऋतु में आरामदायक शीतलता और शरद् ऋतु में सुखद गर्माहट।

कोयरफ़्लेक्स अपनाइए. . . और सुहाने सपनों की सेज सजाइए।

आराम बेमिसाल. . . साल-दर-साल

मैट्रेसस • कुशन • कार्पेट अंडरलेज़

COIRFLEX

Current

कोयर कुशन्स प्रा. लि.

सी-७, नौएड़ा फेस-II, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.)
रजि. आफिस ३६, फंक्शनल इण्डस्ट्रीयल ऐस्टेट फॉर इलैक्ट्रोनिक्स, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-II नई दिल्ली-११००२० फोनः ६३३१०५

- चौधरी बाजार
  कटक-७५३००१
  फोनः २०६४७
- ४०, चौथा क्रास, लालबाग रोड
  के. एस. गार्डन्स,
  बेंगलोर-५६००२७
  फोनः २२०३१८, २२४७०२
- ४१९, व्यापार भवन, पी. डी. मेलो रोड
  कारनक बंदर
  बम्बई-४००००९
  फोनः ३३६२१७, ३२०१४४
- चटर्जी इण्टरनेशनल सेन्टर
  ३-ए, १४वीं मंजिल
  ३३-ए, जवाहरलाल नेहरु रोड
  कलकत्ता-७०००७१, फोन : २११५०६

कुकुरभोज

ऐसे खुशकिस्मत कितने हैं, जिनकी मौत पर लोग आंसू बहायें और चार लोग कंधा देने वाले मिल जायें? फिर किसी का त्रयोदश करना, उसके लिए भोज देना तो बड़ी बात है। किसी इसान के लिए तो यह सब सभव हो भी सकता है, लेकिन किसी जानवर के गुजरने के बाद कोई यह सब करे, तो बात अचरज की है। लेकिन नजीबाबाद के संतोमालन मोहल्ले के देवानंद नामक कुत्ते के मरणोपरांत मोहल्लेवालों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कुछ ऐसे ही किया।

दरअसल देवानंद इतना वफादार था कि पिछले दो सालों से वह मुहल्ले की चौकसी करता था। उसने अपने मुहल्ले में कभी कोई चोरी नहीं होने दी। लेकिन बेचारा इधर दो महीनों से काफी बीमार चल रहा था। मुहल्ले वालों ने उसके इलाज में कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी थी, लेकिन अंततः वह चल बसा। उसकी मौत से मुहल्ले में मातम-सा छा गया। मुहल्लेवालों ने चंदा बटोरकर उसके दाह संस्कार का सरो-समान जुटाया और आत्मीय-जनों की तरह गाजे-बाजे के साथ उसका अंतिम संस्कार किया, जिसमें तकरीबन दो-तीन सौ लोग इकट्ठे हुए। मुहल्लेवालों ने बड़े धूम-धाम से उसकी तेरहवीं की तथा शहर भर के कुत्तों को कुकुरभोज खिलाया।

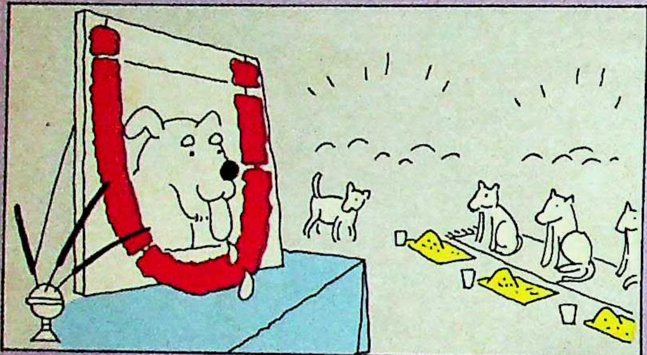

सांप सहचरी

'आस्तीन के सांप' से हर पल खतरा ही खतरा रहता है, लेकिन कोई खतरे से बचने के लिए साक्षात सांप को अपना सहचर बना ले, तो फिर हैरत की बात तो होगी ही। बंबई के एक तकनीकी संस्थान की एक कर्मचारी महिला ने शोह से बचने के लिए सांप को अपना दे प्रहरी बना लिया है।

यों तो इस महिला ने कई तर के जानवर पाल रखे हैं, लेकिन ज वह घर से बाहर बाजार या आफि के काम से निकलती है, तो अपने बै में अपना पालतू सांप रखकर चलती है। यदि कोई मनचला उसे बस या ट्रेन में छेड़ देता है, तो उससे निबटने का काम वह अपने सांप पर छोड़ देती है। उसका कहना है कि ऐसी हालत में सांप से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। मजे की बात तो यह है कि उस महिला अधिकारी ने पुलिस के पास वैसे ही उस सांप का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन किया है, जैसे लोग रिवाल्वर वगैरह के लिए करते हैं, लेकिन पुलिसवाले यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस नियम के अंतर्गत उसे लाइसेंस दें।

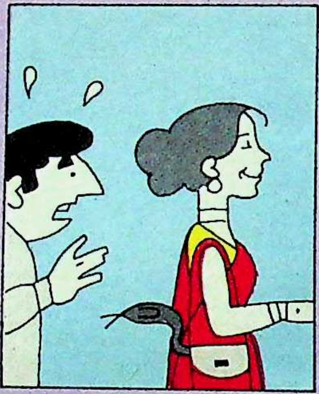

लाखों के बाल

धर्म का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो या न हो, मोक्ष मिले या न मिले, लेकिन तरह-तरह के धंधे खूब चल सकते हैं, यह बात सवा सोलह आने सच है। देखिए न तिरुपति के मंदिरों में आजकल मुंडन किये हुए बालों का धंधा जोरों पर है।

भक्तगण तो अपनी मनौती पूरी होने पर सिर मुड़वाकर चलते बनते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि उनके बालों को बेचकर कितनी रकम प्राप्त की जाती है। अमूमन हर वर्ष बालों की नीलामी होती है और तकरीबन १५ लाख रुपए का व्यवसाय होता है। नीलामी वाले बालों की भी तीन श्रेणियां हैं, प्रथम श्रेणी में वे बाल आते हैं, जो १६ इंच या उससे अधिक लंबे होते हैं, दूसरी श्रेणी में आठ इंच के बाल तथा तीसरी श्रेणी में बिलकुल छोटे बाल आते हैं, जिन्हें आमतौर पर 'कचरा' माना जाता है। लेकिन तिरुपति के इसी कचरे की सबसे अधिक बिक्री बतायी जाती है। नीलामी के बाद बालों को विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है, जहां इससे तरह-तरह की नकली भौंहें, नकली पलकें, तथा विग बनाये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इतालवी बालों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय बालों की सर्वाधिक पूछ है।

सधवा से विधवा

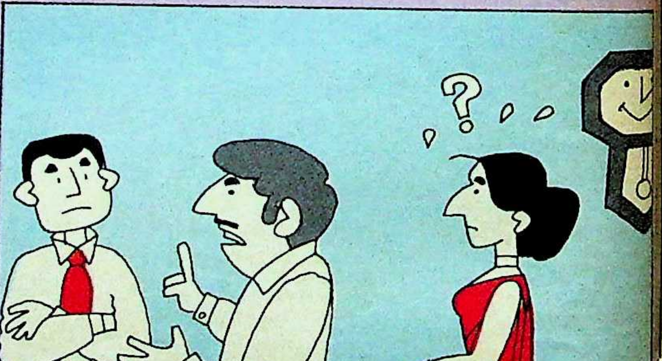

जब डाक्टरी का पेशा 'सोने का अंडे देने वाली मुर्गी' की तरह हो गया है, तब से कौन ऐसा मां-बाप है जो अपनी संतान को डाक्टर न बनाना चाहेगा, लेकिन जैसे-जैसे डाक्टरों का महत्व बढ़ रहा है, वैसे-वैसे मेडिकल कालेजों में दाखिला पाना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में दाखिले के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन एक महिला ने दाखिले के लिए पति के होते हुए विधवा होने का प्रमाण पत्र तक ले लिया। कोयंबटूर के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए ३२ वर्षीया प्रेम आनंदी ने ऐसा ही किया और वह प्रवेश पाने में सफल हो गयी। उसके जीवित पति को जब यह पता चला कि उसकी पत्नी ने ऐसा कारनामा किया है, तो वह अपने जीवित होने तथा स्वास्थ्य ठीक होने का प्रमाण पत्र लेकर अधिकारियों के पास उपस्थित हुआ। लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने साक्ष्य अधिनियम की धारा १०८ के हवाले से तर्क प्रस्तुत किया कि दस साल पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। अतः उसके पति को कानूनन 'मृत' माना जा सकता है। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रेम आनंदी के तर्क को रद्द करते हुए उसका प्रमाण-पत्र अवैध घोषित कर दिया। फलस्वरूप उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

छाया : टीएनए प्रसाद

पंडित रविशंकर

"कला-साधक को कीचड़ में कमल की तरह रहना होता है, अर्थात वह तब तक ऊपर उठता जाता है जब तक संवेदना (सेंस) और वासना (सेक्स) पर नियंत्रण रखता है, पर जैसे ही स्वयं संवेदना और वासना का शिकार होता है वैसे ही डूब जाता है।"

यह बात यदि पं० रविशंकर ने कही है तो अंग्रेजी में ही कही होगी। कला और संस्कृति (खासकर संगीत) की भारतीय परंपराओं, मानदंडों, आदर्शों-अनुशासनों को वे खूब बखानते हैं, कीचड़ में कमल की स्थिति पर वे जोर अवश्य देते हैं, पर 'सेंस' और 'सेक्स' का शिकार भी हो जाते हैं। फिर भी वे डूबते नहीं, यही उनकी खूबी है।

अपनी दूसरी शादी का औचित्य सिद्ध करने के लिए पं० रविशंकर क्या तर्क देंगे, यह तो वही जानें, लेकिन ६९ वर्षीय प्रसिद्ध सितारवादक ने ३८ वर्षीय सुकन्या राजन से ब्याह रचा लिया है।

देश की मिथकीय नगरी काशी में ७ अप्रैल, १९२० को जन्मे रविशंकर नामी बैरिस्टर और विद्वान संगीतकार स्व० श्यामशंकर चौधरी के पुत्र हैं। संगीत इन्हें घुट्टी में ही मिल गया। शुरू में इन्होंने पिता से नृत्य सीखे, बड़े भाई उदयशंकर का अनुसरण किया और ९ साल की उम्र में उन्हीं के साथ विदेश चले गये। उन्हीं दिनों मैहर के महान संगीत-साधक उस्ताद अल्लाउद्दीन खां (बाबा) सालभर के लिए उदयशंकरजी की टीम में आये। उनसे प्रभावित होकर रवि सितार की ओर मुड़े।

बाबा स्वदेश लौट आये। १९३८ में उदयशंकर भी भारत आये। अपने उस्ताद का स्मरण रविशंकर को मैहर खींच लाया। बाबा ने अपने बेटे अली अकबर और रवि में कोई फर्क नहीं किया। एक को सरोद का और दूसरे को सितार का सर्वश्रेष्ठ कलाकार बना दिया। यह जानकर कि रवि ने पहले से ही रिश्ता बना लिया है, बाबा ने अपनी पुत्री ('सुर बहार' की मलका) अन्नपूर्णा से रविशंकर की शादी भी रचा दी।

१९४९ से '५४ तक आकाशवाणी के संगीत निदेशक रहे रविशंकर ने 'राष्ट्रीय वाद्यवृंद (नेशनल आरकेस्ट्रा) और 'शनिवासरीय राष्ट्रीय कार्यक्रम' की स्थापना की, 'बैले' के तहत' 'डिस्कवरी आफ इंडिया', 'सामान्य क्षति' आदि कृतियां लिखीं और पथेर पंचाली, गोदान, काबुलीवाला आदि महत्वपूर्ण फिल्मों में संगीत-निर्देशन किया। बढ़ती शोहरत के साथ रविशंकर ने विशेष निमंत्रण पर विदेश जाकर 'द फ्लूट एंड द ऐरो', 'चप्पकुआ', 'द फेयरी टेल' आदि कई अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में भी संगीत निर्देशन कर स्वयं को विश्वविख्यात बना दिया। १९५८ से अब तक वे बराबर विदेशों में जाते रहे हैं और भारतीय संगीत से विश्व को आकृष्ट करते रहे हैं। देश में किन्नर संगीत महाविद्यालय (बंबई) और 'रिम्पा' इनकी चिरस्थायी स्थापनाएं हैं।

इस बीच कई बार 'संगीत जगत की इस या उस सुंदरी के साथ' रविशंकर के संबंधों की चर्चा उठी और दबी। ये अन्नपूर्णा से अपना संबंध-विच्छेद बहुत पहले कर चुके थे। इस कारण ये व्यापक आलोचना के विषय भी बन चुके हैं। लेकिन इन्होंने किसी आलोचना की परवाह कभी नहीं की। **—वशिष्ठ**

राजलक्ष्मी

दिल्ली जो देश की राजनीति और भविष्य को मोड़ देती है, उसी दिल्ली में दहेज से मौतें भी सबसे अधिक होती हैं। यानी कि दिल्ली हर क्षेत्र में देश के बाकी हिस्सों से आगे होती है। दिल्ली का पुलिस प्रशासन भी इतना प्रगतिशील है कि महिलाओं को नये दायित्व सौंपने के मामले में अपना कोई सानी नहीं रखता।

२१ वर्षीया सर्वजीत कौर को पहली महिला ट्रैफिक पुलिस के रूप में विजय चौक पर यातायात का दक्षतापूर्वक नियंत्रण करते देखना एक सुखद अनुभव है, तो अब डिफेंस कालोनी थाने की प्रभारी के रूप में इंसपेक्टर राजलक्ष्मी भी उसी पंक्ति में आ खड़ी हुई हैं। उनका महत्व इस लिए बढ़ गया है, क्योंकि थाना प्रभारी के पद की जिम्मेदारी अभी तक किसी स्त्री को नहीं सौंपी गयी थी। पुरुष के इस एकाधिकार क्षेत्र में सेंध लगानेवाली राजलक्ष्मी पहली महिला इंसपेक्टर हैं। ३८ वर्षीया राजलक्ष्मी सितंबर १९७३ में दिल्ली पुलिस में शामिल हुई थीं। वे लेडी इर्विन कालेज से विज्ञान की स्नातक हैं।

राजलक्ष्मी थाना प्रभारी नियुक्त होते ही सुर्खियों में आ गयी हैं। पर इसके पूर्व वे तब अधिक चर्चा का विषय बनी थीं, जब १९८२ में श्रीमती गांधी के सुरक्षा दस्ते में एक सब-इंसपेक्टर के रूप में अमरीका गयी थीं और लौटने पर हवाई अड्डे पर अपने भारी भरकम सूटकेसों के कारण विवादास्पद हो गयी थीं।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

कल्पना पंडित

खूबसूरत होना एक बात है, पर खूबसूरत चेहरों के बीच किसी चेहरे द्वारा खूबसूरत होने का खिताब पाना अलग बात है। ऐसे ही सम्मान की हकदार बनी हैं मैसूर की इक्कीस वर्षीया मेडिकल छात्रा कल्पना पंडित। बंबई की एक अंग्रेजी महिला साप्ताहिक पत्रिका तथा गरवारे वीडियो कैसेट कंपनी द्वारा १४ जनवरी '८९ को बंबई में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में कल्पना पंडित १९८९ की 'मिस इंडिया' चुनी गयीं।

छाया : शर्मा स्यामसुंदर

डाक्टर बनने की चाहवाली कल्पना पंडित (एमबीबीएस की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं) भरतनाट्यम की नृत्यांगना होने का गौरव भी रखती हैं। वे तेरह वर्ष की उम्र से ही इस कला की साधिका हैं। सुखद बात यह भी है कि चिकित्सा से जुड़े परिवार की कल्पना पंडित (पिता जाने माने फिजीशियन हैं) बाल रोग विशेषज्ञ बनना चाहती हैं। वैसे इन दिनों वे अगली जुलाई में टोकियो में होनेवाली विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी में जुटी हुई हैं। जिसमें ५० देशों की सुंदरियां विश्व सुंदरी बनने के लिए अपना भाग्य आजमायेंगी। **— दिनेश दीनू**

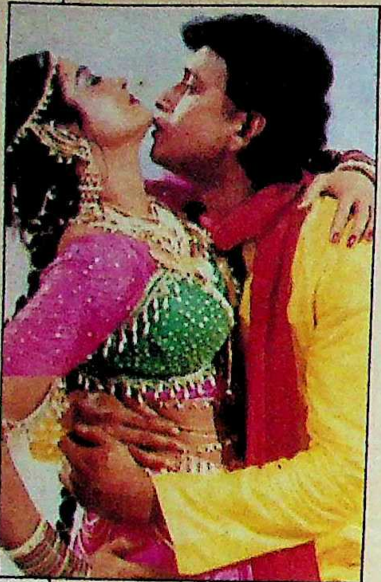

भानुप्रिया और मिथुन चक्रवर्ती

भानुप्रिया की बंबई वापसी

निर्माता विमल कुमार ने जब मिथुन चक्रवर्ती के भाग्य को संवारने के लिए अपनी नयी फिल्म में भानुप्रिया को पहली बार साइन कर फिल्म का निर्माण शुरू किया, तो भानुप्रिया के इडली-डोसा सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि मद्रास की अन्य हीरोइनों की तरह वे तभी हिट हो सकती हैं, जब उनके हीरो जीतेंद्र और डायरेक्टर क़ोई 'दक्षिणिया' हो। तब मिथुन के हाथों अपने कैरियर की शुरुआत खतरे में समझ भानुप्रिया विमल कुमार की निर्माणाधीन फिल्म को बीच में रोक कर चुपचाप मद्रास खिसक गयीं और टी रामाराव की फिल्म 'दोस्ती-दुश्मनी' में जीतेंद्र के साथ छोटी-सी भूमिका में काम करने लगीं, फिर जीतू की सलाह पर उसकी पत्नी की छोटी-सी भूमिका 'खुदगर्ज' भी निभा लिया और अपने को पहली बार साइन करने वाले निर्माता को लटकाये रखीं। इन दोनों छोटी भूमिकाओं ने भानु के कैरियर को जब धुंध में ढकेल दिया, तो श्रीदेवी बनने की चाह में बंबई आयीं भानु को विमल कुमार की याद आयी।

इसे कहते हैं, 'उड़ि जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आये,' शायद भानु इस कहावत का अर्थ पूछने भी अपने इडली-डोसा सलाहकारों के पास पहुंच जायें!

किमी कातकर : नयी वाटर बेबी !

किमी कातकर ऐसी हीरोइन हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक दिन में छह (पूरे महीने में ११) फिल्मों का मुहूर्त कर सभी नबंरवन हीरोइनों (श्रीदेवी, रेखा, डिंपल कपाड़िया तथा जयाप्रदा—सिर्फ एक-एक फिल्मों का मुहूर्त) को न केवल काफी पीछे छोड़ दिया, बल्कि एक नया कीर्तिमान भी कायम किया। अगर वे ओलंपिक में यह करतब दिखलातीं, तो शायद उन्हें सिर्फ एक स्वर्ण पदक से संतोष कर लेना पड़ता, लेकिन यहां तो पहले से उनकी झोली में पड़े ५० फिल्मों के साथ ११ फिल्मों के स्वर्णपदक और भी जुड़ गये। अगर उनकी सभी फिल्में सचमुच सेट पर चली जायें, तो इन फिल्मों के लिए वे डेट २१वीं सदी में ही दे पायेंगी।

किमी और विनोद खन्ना

यों किमी ने एक और कीर्तिमान कायम किया—उन्होंने छहों मुहूर्त शाट स्वीमिंग सूट में तथा स्वीमिंग पूल पर बड़े आराम से दिये। किमी एक पंचसितारा होटल के स्वीमिंग पूल से निकलतीं, स्वीमिंग सूट बदल कर दूसरा पहनतीं फिर दूसरे होटल के स्वीमिंग पूल में पहुंच जातीं। उनकी यह काबिलीयत देखकर अब तो उन्हें 'वाटर बेबी' का खिताब जरूर मिलना चाहिए!

स्वप्ना

छाया: डीआर यादव

स्वप्ना की खातिर

निर्माता सत्ती शौरी तथा अभिनेत्री स्वप्ना के आपसी महाभारत ने सत्ती के सामने नयी मुसीबतें पैदा कर दी हैं और उनकी बहुसितारीय फिल्म 'फरिश्ते' खटाई में पड़ गयी है। सत्ती के 'मर्दाने व्यवहारों' से जरूरत से ज्यादा कुंठित हास्य अभिनेता मुकरी तथा स्वप्ना लोगों को रो-रोकर सत्ती द्वारा अपने साथ किये गये 'बरताव' की रामायण सुना कर अपने दुख के आंसू पोंछ ही रहे थे कि एक और सत्ती-पीड़ित राजेंद्रनाथ सीधे, जहांगीर (धर्मेंद्र) और नूरजहां (श्रीदेवी) के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे गये। उनका दुखड़ा था—'फरिश्ते' की शूटिंग के लिए उन्हें पहलगाम बुलाया गया, लेकिन उनके एक भी सीन की शूटिंग नहीं हुई, इसलिए कह दिया कि 'नो वर्क नो पेमेंट।' अब खाली जेब राजेंद्रनाथ वहीं शूटिंग कर रहे नितिन मनमोहन के पास पहुंचे और गिड़गिड़ा कर बोले, "माबदौलत, कोई भी रोल दे दीजिए बदले में सिर्फ बंबई तक हवाई टिकट और होटल का पेमेंट अता फरमा दीजिए बसं।" नितिन को बेचारे राजेंद्रनाथ पर दया आ गयी, उन्होंने उन्हें हिजड़े का रोल देकर उनकी परेशानी हल कर दी।

इस सारे वाकयात से नाराज जहांगीर तथा नूरजहां अभी कोई फैसला सुनाती कि 'फरिश्ते' के निर्देशक अनिल शर्मा स्वप्ना को लेकर अपनी खुद की फिल्म 'ऐलान-ए-जंग' शुरू कर दी है। आखिर झगड़े की जड़ स्वप्ना थी जिन्हें सत्ती शौरी ने अनिल शर्मा की रखैल कह दिया था!

बेनजीर बनीं जयाप्रदा

शबाना आजमी अभी बेनजीर भुट्टो की फिल्मी भूमिका निभाने का सपना संजो ही रही थीं कि जयाप्रदा ने बाकायदे बेनजीर के लिबास और भूमिका में शूटिंग शुरू कर दी। निर्माता-निर्देशक चंदर शर्मा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी से कुछ इस कदर प्रभावित हुए कि आनन-फानन 'धर्मज्योति' की शूटिंग शुरू कर दी। अब जयाप्रदा भी बेनजीर से कुछ इस कदर प्रभावित थीं कि उन्होंने भी अपनी कई फिल्मों की शूटिंग रद्द कर डेट्स 'धर्मज्योति' को थमा दी, ताकि फिल्म तीन-चार महीने में बन जाये। इस फिल्म में भुट्टो के पति की भूमिका निभा रहे हैं, जीतेंद्र तथा जुल्फिकार अली भुट्टो बने हैं, चरित्र अभिनेता जानकीदास। इसमें राज बब्बर बेनजीर के दोस्त की भूमिका निभायेंगे।

जयाप्रदा

छाया: तैयब बादशाह

—अखबारी लाल

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

धूम मचा दे... रंग जमा दे.
PAN PARAG
पान पराग
स्वादिष्ट
सादे पान का मसाला
पान पराग
स्वादिष्ट
पान मसाला

आपका मनपसंद पान पराग,
डिब्बे और सुविधाजनक पाउच में.

अब स्वादिष्ट पान पराग जैसे चाहें वैसे लीजिए. डिब्बे या पॉकेट पाउच में... जहाँ जी चाहे ले जाइए — लुत्फ़ उठाइए. और पसंदीदा पान पराग के साथ ज़िंदगी की मौज-मस्ती का मज़ा लीजिए.

पान पराग®
पान मसाला

भारत का सब से अधिक बिकने वाला पान मसाला

कोठारी उत्पादन

everest/d89/KP/15 hin

DUPLICATE

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

9/3/84

तकनीक में उत्तम - बनावट में सर्वोत्तम

उच्च तकनीक से
इलास्टिक तैयार,
बनावट को रखे बरकरार

अधिक मुलायम
मर्सिराइज्ड कॉटन

मनमोहक रंगों में, केवल आपके लिये

हर मौसम के लिये उपयुक्त,
फूल सी कोमल

डोरा®
आराम • गुणवत्ता • विशिष्टता... एक साथ

एच.पी. टेक्सटाईल मिल्स कलकत्ता • नई दिल्ली • अहमदाबाद • कानपुर • बम्बई

Ankur/HPT/489-HIN

माया

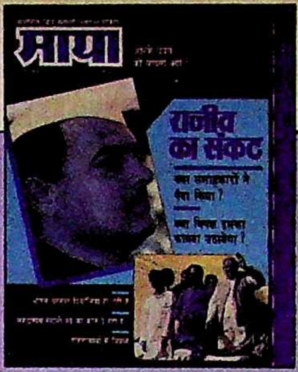

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ६०, अंक ५ १५ मार्च, १९८९

आवरण कथा

२९

कांग्रेस-इ में उफनते विद्रोह के कारण राजीव गांधी अभूतपूर्व संकट में फंस गये हैं। क्या यह संकट उन्हीं लोगों ने उपजाया है, जिनको यह संकट मिटाने का काम सौंपा गया था? क्या आरके धवन की वापसी इस बात का संकेत है कि राजीव गांधी ने यह समझ लिया है कि उनके वर्तमान सलाहकार निष्पक्ष नहीं? राजीव के इस संकट को भुनाने के लिए विपक्ष क्या रणनीति अपनायेगा?

१७ नौकरशाही

नौकरशाहों के जरिये राजनीतिक हित सिद्ध करने के कारण प्रशासन की हालत क्या हो रही है?

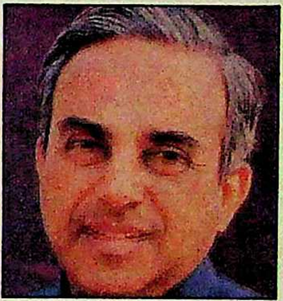

२३ स्वामी

सुब्रह्मण्यम स्वामी को विपक्षी नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए हर्शमैन से प्राप्त दस्तावेज किसने दिये?

८७ कंगाली

सरकार ने ऐसी कौन सी घातक आर्थिक नीतियां अपनायीं कि सरकार दिनोदिन दिवालिया हो रही है?

६५ इंका महाधिवेशन

१० फरवरी को लखनऊ में संपन्न उप्र इंका महाधिवेशन सत्तारूढ़ दल की कैसी सूरत पेश करता है?

५३ शंकराचार्यों का विवाद

नर्मदा-तट पर ओंकारेश्वर मंदिर के निकट जिस गुफा में आद्य शंकराचार्य ने गुरुदीक्षा ली थी, उस पर इतना विवाद क्यों है?

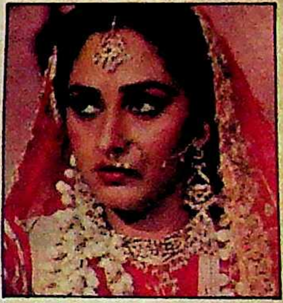

९४ फिल्म

क्या कारण है कि बंबई की फिल्मी दुनिया में आज भी दक्षिण की अभिनेत्रियों का ही वर्चस्व है?

दिल्ली दरबार : पंचों का फैसला, सिर माथे पर, लेकिन १०
फोटोफीचर १३
विशेष : आरके धवन की वापसी क्यों? ३८
स्त्री : लड़के-लड़कियां कितना करीब आयें? ४१
पंजाब : फांसी पर ऐसे लटकाये जाते हैं लोग ४४
महाराष्ट्र : दो दुश्मनों के बीच जनता दल ४७
बिहार : इस्पात नगरी में उठे हक के सवाल! ४९
बिहार : गिरोहों की गिरफ्त में जमशेदपुर ५१
मध्य प्रदेश : विपक्ष को इंका का आसरा ५६
राजस्थान : विद्युत संकट के कगार पर ५९
राजस्थान : आखिर जीत इब्राहीम की हुई! ६१
उत्तर प्रदेश : सांखनी में पुलिस की मौजूदगी में नरसंहार ६९
उत्तर प्रदेश : पंतनगर विश्वविद्यालय : जातीय झगड़ों का अखाड़ा ७२
खेल : स्टिक किसी के पास, गेंद किसी के पास ७६
देश : आजाद की पदयात्रा का मतलब ८१
दूरदर्शन : 'महाभारत' का महाभारत ८३
अर्थतंत्र : राहत की सांसत ९१

आवरण पारदर्शी
मनमोहन शर्मा
(राजीव गांधी)
शिरीष श्रीवास्तव
([illegible])

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
ब्यूरो प्रमुख
बंबई : रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ : अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना : विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ : सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल : सुधीर सक्सेना
जयपुर : ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

---

० प्रधान कार्यालय : २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन : ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स : ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय : ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन : ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स : ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय : बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन : ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय : ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन : २६७४०, भोपाल कार्यालय : एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन : ६६३८८, बंबई कार्यालय : ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन : २४३५७७, तार : माया कहानी, टेलेक्स : ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय : स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन : २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©

इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

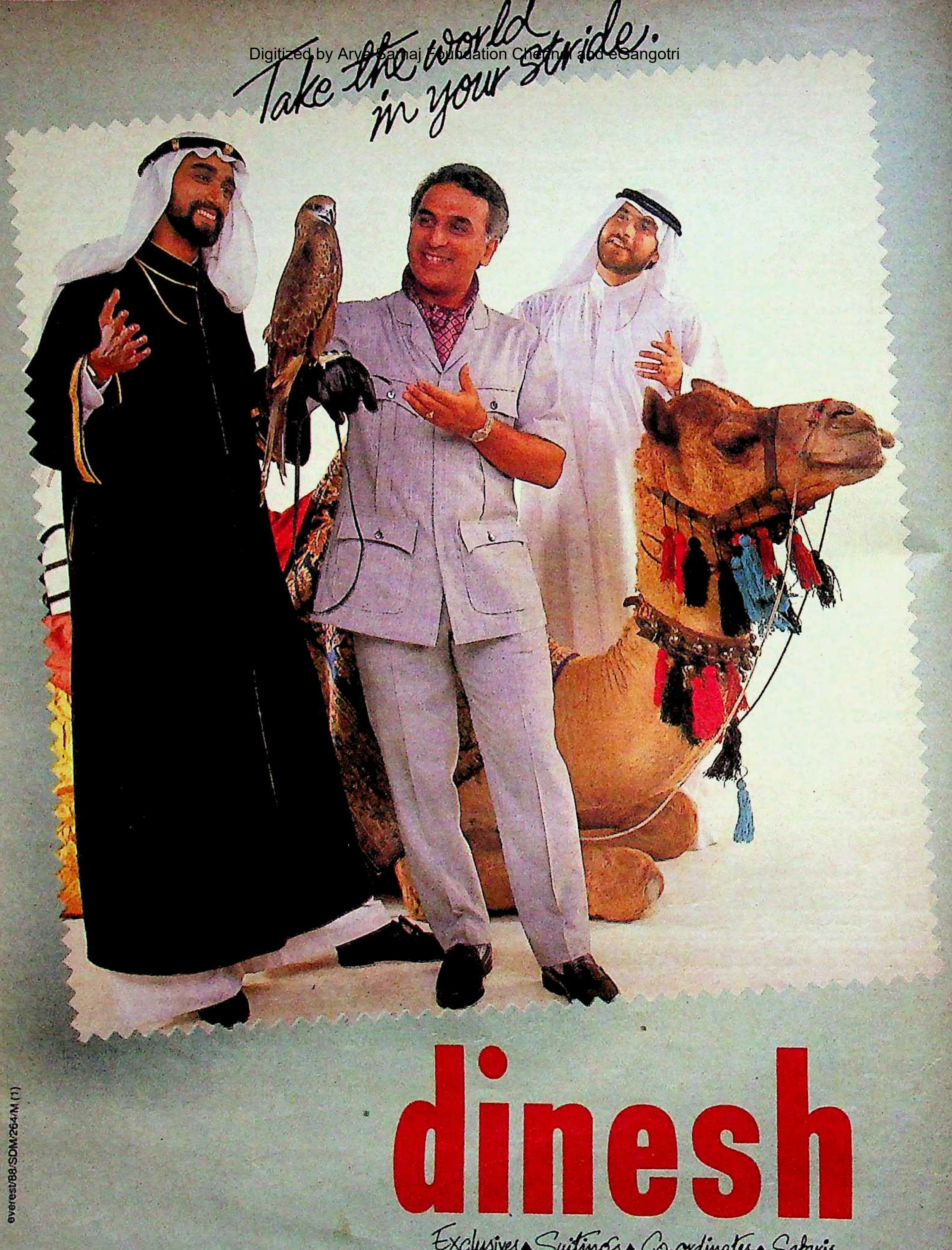
Take the world in your stride.

dinesh

Exclusives ▲ Suitings ▲ Co-ordinates ▲ Safaris

The choice of leading fashion houses, internationally.

Authorised dealers : **JAINAGAR** : Danmal Barolia • **JHARIA** : Bharat Cloth Stores • **MUZAFFERPUR** : Binod Vastralaya • Fancy Vastralaya • Manjushree • Neelkamal • Roopsaree Kendra • Shree Hanuman Textiles • Shri Arun Vastralaya • Sidharth • Shubhlaxmi.

everest/88/SDM/264/M (1)

कांग्रेस में खुली बगावत

'**मा**या' का ताजा अंक (२८ फरवरी, १९८९) मिला। आवरण कथा 'कांग्रेस में खुली बगावत : क्या राजीव संभाल पायेंगे?' पढ़ी। 'माया' ने कांग्रेसी प्रांतों मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान में चल रहे विद्रोह का जो खाका खींचा है, उससे राजीव गांधी की स्थिति डांवाडोल लगती है। इस विद्रोह का असली रूप तो आगे आनेवाले आम चुनाव में ही उजागर होगा। लेकिन हमें बहुत आशा विपक्ष से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी विद्रोहों या असंतोषों से मुक्त नहीं है। पक्ष-विपक्ष तो जो भी करें, किसी-न-किसी को इन्हीं में से सत्ता में आना है, लेकिन असली दुर्दशा तो जनता की है, जिस पर कोई नेता तवज्जह नहीं देता। **—दिग्विजय सिंह, फिल्म ऐंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, उड़ीसा**

बिहार का शिक्षा माफिया

बिहार का शिक्षा-माफिया पढ़ा। विकास जी ने निष्पक्ष होकर शिक्षा माफिया के काले कारनामों का रहस्योद्घाटन किया है। अफसोस इस बात का है कि शिक्षा माफिया के सफाये का बीड़ा उठानेवाले मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के मंत्रिमंडल में भी शिक्षा माफिया के एक सदस्य शिक्षा विभाग की बागडोर संभाले हुए हैं, चोर को ही चौकीदारी सौंपी गयी है। मुख्यमंत्री इतने असहाय साबित हुए कि उनकी इच्छा के विपरीत एक ईमानदार कुलपति बर्खास्त कर दिये गये। **—विमल मालाकार, बरारी, गुरुबाजार, कटिहार**

दमन बनाम स्वतंत्रता

१५ फरवरी की 'माया' में 'दमन बनाम स्वतंत्रता' पढ़ा। सफदर हाशमी जैसे कुशल अभिनेता, निर्देशक, गायक, वक्ता की हत्या कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।

हाशमी समाज की सड़ी-गली मान्यताओं को ललकारनेवाले थे। व्यवस्था से अव्यवस्था हटाने की बात सोचनेवाले थे। एक ऐसी ही सोच को समाज के सम्मुख 'हल्लाबोल' के मंचन के माध्यम से लाने की तैयारी में थे कि व्यवस्था से जुड़े अव्यवस्था फैलानेवालों के गिरोह ने उनके प्राण ले लिये। लोकतंत्र, समाजवाद व अभिव्यक्ति की आजादी का दम भरनेवाली कांग्रेस का नगरपालिका चुनाव में यह रवैया है, तो लोकसभा चुनाव में भला क्या होगा? वे लोग हमारे बीच में कोई और हाशमी खोज रहे हैं, हथियारों से लैस होकर। इससे पहले कि कोई और हाशमी शहीद हो, हम एक दूसरे के हाथ आपस में कस लें, उनके सामने खड़े हो जायें, उनकी बंदूकें तोड़ दें और एक स्वर में पूरी दुनिया में चिल्ला दें—"अब कोई सफदर हाशमी नहीं मरेगा।" **—जयंत कुमार बारीक, महलपारा, सरायपाली, रायपुर, मध्य प्रदेश**

सफदर हाशमी हत्याकांड पर आपकी रिपोर्टिंग अत्यंत वास्तविकतापरक और मार्मिक रही। सफदर हाशमी जैसे मेधावी, देशभक्त और कटुसत्य को उजागर करते रहने का दृढ़ संकल्प लेनेवाले कलाकार की हत्या और वह भी इतने वीभत्स तरीके से की गयी कि पैशाचिकता भी कोसों पीछे छूट गयी है। **—वैद्यनाथ पाण्डेय, राजकीय औषधालय, बिहिया, भोजपुर**

रैलियों की राजनीति

१५ फरवरी की 'माया' में 'रैलियों की राजनीति' पढ़ी। इटावा में ५ फरवरी को जनता दल की रैली में उमड़ा विराट जनसमूह इस बात की पूर्व सूचना दे रहा था कि जनता कांग्रेस के विरुद्ध अपना मत देने को तैयार है, लेकिन किसे अपना वोट दे? अपने को खाई और कुएं के बीच पाकर वह निराश हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अंतर्कलह से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में नाक सीधी पकड़ी जाये या घुमाकर बात एक ही बनती है। फिर भी कुछ अंतर तो जरूर है। एक की रैलियों में भीड़ खींचकर लायी जाती है, तो दूसरी ओर जनता खिंचती सी चली आती है। यदि जनता दल ने जनता का विश्वास जीत लिया, तो क्या ये (जनता दल के नेता) अंतर्कलह छोड़कर देश का नेतृत्व कर पायेंगे? **—प्रेमसिंह रावत, ग्राम बीरो, बसुकेदार, चमोली, उत्तराखण्ड**

१५ फरवरी की 'माया' में 'रैलियों की राजनीति' पढ़ी। जनता दल की रैलियों का विश्लेषण और एक दूसरे की उठा-पटक का विश्लेषण काफी रोचक लगा। लेकिन आज आम मतदाताओं को जरूरत है एक संयुक्त विपक्ष की जो अनुशासित, कार्यक्षमतावान और निष्ठावान हो। जो अंतर्कलह से मुक्त हो। अभी तक वर्तमान संयुक्त विपक्ष असली रूप में एक होकर मतदाताओं के पास नहीं आया है। विपक्षी नेताओं को चाहिए कि वे एक जुट होकर आपसी भेदभाव, पदलोलुपता, भाई-भतीजावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को परे रखकर मतदाताओं के सामने एक ऐसा ढांचा रखें, जिससे आम मतदाता उस पर अपनी आस्था रख सके। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो एकता की बात भर करने से कुछ नहीं होनेवाला है। **—शिवराज पटेल, चुरहट, सीधी, मध्य प्रदेश**

शिवसेना का तृतीय अधिवेशन : आम चुनाव जीतने का रिहर्सल

१५ फरवरी '८९ की 'माया' में प्रकाशित लेख 'शिवसेना का तृतीय अधिवेशन : आम चुनाव जीतने का रिहर्सल' पढ़ा, जो अनेक राजनीतिक तथ्यों से परिपूर्ण है। इस संबंध में एक तथ्य यह भी है कि हिंदू धर्म की आड़ में राजनीतिक पार्टियां बनाकर लोग कुरसी हासिल करने का गंदा खेल खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आज संपूर्ण भारत वर्ष में हिंदू धर्म की आड़ लेकर कुरसी हासिल करने का यह घिनौना खेल कब बंद होगा? यदि यह धंधा चलता रहा, तो धर्म पर से विश्वास खतम हो जायेगा। **—सत्यनारायण चतुर्वेदी, बनारसी घाट, बाढ़, पटना**

मीडिया ने अहम मुद्दे क्यों नहीं उठाये?

१५ फरवरी की 'माया' में 'मीडिया ने अहम मुद्दे क्यों नहीं उठाये?' पढ़ा। लेख काफी चुनौतीपूर्ण एवं कानून की बारीकियों को आलोकित करते हुए लिखा गया है। वास्तव में कई दैनिक पत्रों एवं इलेस्ट्रेटेड वीकली ने केहर सिंह से साक्षात्कार करके, यह आम धारणा लोगों के बीच फैला दी थी कि केहर सिंह निर्दोष है। पर अभय अग्रवाल की रिपोर्ट 'फैसले पर संदेह क्यों?' यह आभास दिलाती है कि केहर सिंह इंदिरा हत्याकांड से पूर्व अवगत था। वास्तव में हत्या का षड्यंत्रकारी या हत्या से अवगत व्यक्ति हत्यारे से भी ज्यादा गुनहगार होता है। **—जग नारायण सिंह 'पंकिल', उदयप्रताप कालेज, वाराणसी**

कुछ सवाल

'**मा**या' के १५ फरवरी, १९८९ अंक में आपने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले 'महाकुंभ' पर फोटोफीचर देकर निश्चय ही अपनी धार्मिक प्रवृत्ति का अनूठा एवं प्रशंसनीय परिचय दिया, लेकिन दूसरी ओर आपने ममता कालिया का लेख ('कुंभ और नारी') देकर अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को ठेस पहुंचायी है। ममताजी के छपे विगत कई एकपक्षीय ('स्त्री') लेखों से लगा कि वह पुरुषों के पीछे बुरी तरह पड़ गयी हैं और इस लेख ('कुंभ और नारी') में तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघते हुए अपने मनगढ़ंत विचारों के माध्यम से महाकुंभ जैसे अनुष्ठान पर करारी चोट पहुंचायी है। **—राजकुमार यादव, मगरधा, बीना, मप्र**

पुरुष को भी तरजीह दें

'**मा**या' के १५ फरवरी वाले अंक में 'स्त्री' स्तंभ के अंतर्गत ममता कालिया के विचार पढ़े। आज स्वयं को 'प्रगतिशील' माननेवाला प्रत्येक लेखक अनुचित रूप से नारी के संदर्भों में सदैव पुरुष को ही दोषी ठहराता है। श्रीमती कालिया भी अपवाद नहीं हैं और अपने हर लेख की तरह इस बार भी उन्होंने पुरुष पर मिथ्या-दोषारोपण किया है। लेखिका का मत है कि 'पुरुष ने पाप-पुण्य की भावना गहराई से नारी के दिमाग में बैठा दी है' और नारी की अवधारणा ही पाप से लिप्त है। पता नहीं वे किस नजरिये से सोचती हैं। सच तो यह है कि नारी हर क्षेत्र में पुरुष की अपेक्षा पीछे है और इसी प्रकार आज भी नारी 'अंधश्रद्धाभक्ति' में विश्वास रखती

◆ चिट्ठियां

हैं बनिस्वत पुरुष के। **—मनोज श्रीवास्तव, विदिशा, मध्य प्रदेश**

नारीशाला का गड़बड़झाला

१५ फरवरी, १९८९ की 'माया' में 'नारीशाला का गड़बड़झाला' सत्यता पर आधारित रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि असहाय महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नारीशाला केंद्रों को हरमुखसिंह जैसे नरपिशाचों ने व्यभिचार और अय्याशी के अड्डों में बदल दिया है। सरकार को चाहिए कि हरमुख सिंह, सुधीर कुमार और प्रेमलता वर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दे। कोरे निलंबन से काम नहीं चलेगा। काश! हमारे यहां भी ईरानी कानून होता। **—सुभाष मेहता, चौपाटी जावरा, जिला—रतलाम, मध्य प्रदेश**

कम उम्र, पर लंबी पारी

'माया' का १५ फरवरी का अंक पढ़ा। इस अंक में स्कूली क्रिकेटर 'सचिन तेंदुलकर' के बारे में पढ़ा। वास्तव में वह आनेवाले समय में चमकेगा। उसने अपने पहले ही रणजी मैच में बंबई से गुजरात के विरुद्ध शतक बनाने के साथ-साथ अगले मैचों में भी आकर्षक पारी खेली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वह आगे चलकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी का कर्णधार बनेगा। **—धर्मेंद्र कुमार दुबे, बड़हलगंज, गोरखपुर**

बड़ा साधु कौन?

'माया' (१५ फरवरी) के फोटोफीचर में संन्यासियों की शोभायात्रा देखकर मन साधु-संन्यासियों के प्रति वितृष्णा व ग्लानि से भर उठा। ये कैसे ज्ञानी, परमार्थसेवी व धर्मोपदेशक साधु हैं, जो स्वयं बड़े-बड़े रथों पर सुसज्जित व सवार हो इंसानों से अपने बोझ को खिंचवाते हैं? नंगे-पांव, पसीनों से तर-बतर इंसानरूपी देवताओं को कष्ट देकर किस देवता को खुश करने जा रहे हैं? ऊपरी शानो-शौकत, दिखावा छोड़कर मानव-मात्र को प्रतिदिन लाखों रुपयों का अन्न व कपड़े बांटनेवाला गुजराती, मारवाड़ी गृहस्थ बड़ा साधु है, बड़ा संन्यासी है। **—पवन सुरैका, त्रिनगर, दिल्ली**

हाथी घोड़ा पालकी जय बहुगुणा लाल की

१५ फरवरी, १९८९ की 'माया' में दिल्ली दरबार के अंतर्गत प्रकाशित 'हाथी घोड़ा पालकी जय बहुगुणा लाल की' शीर्षक लेख बहुत ही अच्छा लगा। हिंदी में प्रकाशित अन्य पत्र-पत्रिकाओं में इस तरह का राजनीतिज्ञों पर व्यंग्य नहीं होता है, जबकि 'माया' में कमाल का होता है। **—सुधीर कुमार झा, जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय, कटहरी, विराटनगर, नेपाल**

केबिल टीवी के खतरे

'माया' के नवीनतम अंक में केबिल टीवी द्वारा बड़े बजट की फिल्मों को होनेवाले नुकसान के बारे में रवींद्र श्रीवास्तव का लेख पढ़ा। लेखक ने वास्तव में एक नयी समस्या उठायी है। हालांकि यह बीमारी अभी महानगरों तक ही सीमित है, लेकिन बड़े शहरों व कस्बों को अभी से इसकी रोकथाम कर लेनी चाहिए। हालांकि ये मनोरंजन के अच्छे साधन हैं, लेकिन फिर भी इनके बड़े कुप्रभाव भी हैं। **—हर्षकुमार, ३६ देवपुरम्, मुजफ्फरनगर, उप्र**

◆ खयालात

वे (सुब्रह्मण्यम स्वामी) अपनी इस खोजी रिपोर्ट (कि मैंने विदेश में धन जमा किया है) को अपने मित्र राजीव गांधी को सौंप दें जिन्हें (मुझ पर) मुकदमा चलाने के लिए मैं चुनौती देता हूं। **—रामकृष्ण हेगड़े**

बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, वे मुगल साम्राज्य के आखिरी दिनों की याद दिला रही हैं। **—अजीत सिंह, रायबरेली में**

विपक्ष का गठबंधन सांप्रदायिक है, उसके नापाक इरादों को कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी कामयाब नहीं होने देंगे। **—नारायणदत्त तिवारी, लखनऊ (उप्र इंका समिति के अधिवेशन) में।**

चुप रहिए, (जोर से) चुप! ... मैं जब उत्तर प्रदेश आता हूं, तो इसी भाषा का इस्तेमाल करता हूं। **—इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद, लखनऊ में**

राजीव गांधी सिर्फ फेरबदल के तिकड़म पर टिके हैं। वे अपने काबीना में २४ बार फेरबदल कर चुके हैं और अब फेरबदल की रजतजयंती मनानेवाले हैं। **—देवीलाल, हैदराबाद में पत्रकारों से वार्ता के दौरान।**

रामकृष्ण हेगड़े

विश्वनाथ प्रताप सिंह

वे (राजीव) पराजय का प्रतीक बन गये हैं। मुख्यमंत्रियों को आधी रात में बदलने का रवैया अपनाकर, मानो वे दिन के प्रकाश का सामना करने से कतरा रहे हैं। **—विश्वनाथप्रताप सिंह, कलकत्ता (प्रेस-वार्ता) में।**

कम्युनिस्ट खेमे में अब भी एक ऐसा तबका है, जिसे यह चिंता खाये जा रही है कि कांग्रेस सरकार अब जानेवाली है। **—भाजपा प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी, दिल्ली में**

माकपा की विडंबना यह है कि वह हमेशा लेनिनवादियों के खिलाफ कतारबंदी करती रही है। **—इंका महासचिव केएन सिंह, कलकत्ता में (सभा को संबोधित करते हुए)**

(केएन) सिंह दरअसल बेवफा माशूक द्वारा ठुकराये जाने से चौंके हुए आशिक के हालात से गुजर रहे हैं। वे माकपा में कभी खुद रह चुके हैं, पर अब सवाल उठा रहे हैं कि माकपा उनकी पार्टी (इंका) को ठुकरा कर (राष्ट्रीय) मोर्चे को तरजीह क्यों दे? **—भाजपा सचिव जेपी माथुर और वीके मल्होत्रा, दिल्ली (संयुक्त वक्तव्य) में।**

मैं कोई राय-वाय नहीं देता, क्योंकि मेरी राय कोई नहीं मानता। **—चंद्रशेखर, दिल्ली में (सुब्रह्मण्यम स्वामी को शह देने के सवाल पर)**

मेरे शौहर ने ग्यारह सालों के लंबें अरसे तक इस मुल्क की [illegible] की तरह समर्पित होकर, खिदमत की और अब ये (यहीं के) लोग उन्हें तानाशाह कह रहे हैं। **—जनरल जिया की विधवा बेगम शफीका, इस्लामाबाद (साक्षात्कार) में**

सबसे हैरतअंगेज चीज तो यह है कि वे ('सैटनिक वर्सेस' से बिदके पाकिस्तानी कट्टरपंथी) लोग एक ऐसी किताब का जिक्र करते हैं जो है ही नहीं। **—लेखक सलमान रुशदी, लंदन ('गार्जियन') में**

दिल्ली अब दूर नहीं, आप नेशनल फ्रंट को वोट दीजिए और हम कांग्रेसी लीडरों को उठाकर जमुना में फेंक देंगे। **—एनटी रामाराव, गुवाहाटी (अगप रैली) में**

मैं जब साड़ी को छूता हूं, तब बहुत उदास हो जाता हूं। यह बेहद खूबसूरत होती है, इसको छूना ऐसा ही है जैसा एक मासूम जान को मार डालना। **—प्रसिद्ध डिजाइनर पियरे का दिन, बंबई (साड़ी-प्रदर्शनी) में।**

जायें तो जायें कहां? **—अटल बिहारी वाजपेयी, संडे आब्जर्वर में (भाजपा छोड़ने की संभावना पर)।**

एक-एक कर कई लड़के चुने मैंने, पर हर बार ऐसे हालात पैदा हो गये कि मुझे लगा, मैं बिनब्याही ही भली हूं। **—अभिनेत्री अरुणा ईरानी**

यह बचत का महान साधन है

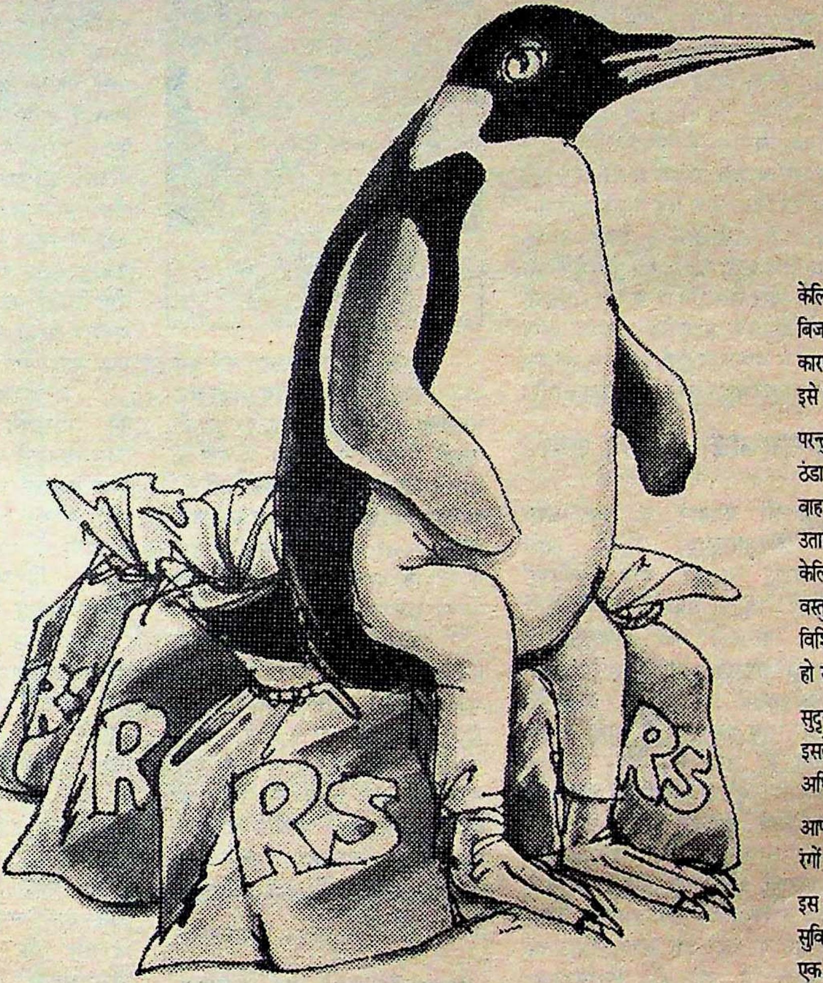

केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर का सब से किफायती गुण है इसकी बिजली की कम खपत। अपने 'पावर-सेवर' काम्प्रेसर के कारण यह अपनी ख्याति की कसौटी पर खरा उतरता है। इसे चलाते ही, यह बचत करनी शुरू कर देता है।

परन्तु 'पावर-सेवर' मात्र बचत ही नहीं करता। यह शीघ्र ठंडा करता है तथा उससे भी शीघ्र बर्फ़ बनाता है। चाहे वाहर का तापमान कुछ भी हो। वोल्टेज का कितना भी उतार चढ़ाव इसके कुशल कार्य में विघ्न नहीं डाल सकता। केल्विनेटर का एक और आश्चर्यजनक गुण है — इसमें वस्तुएं रखने की विशाल क्षमता। इसके कोने-किनारे-रहित विशिष्ट अन्दरूनी डिज़ाइन में अधिकतम स्थान का उपयोग हो सकता है।

सुदृढ़, सम्पूर्ण स्टील निर्माण तथा मज़बूत ए बी एस लाइनर इसके बाहरी एवं अन्दरूनी भाग को अधिक मज़बूती तथा अधिक टिकाऊपन प्रदान करते हैं।

आपके चयन के लिए यह विभिन्न माडलों तथा आकर्षक रंगों में उपलब्ध है।

इस कारण, केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रस्तुत इन सभी सुविधाओं के साथ, यह मात्र बचत साधन ही नहीं यह एक रक्षक है।

विक्रय एवं सर्विस के लिए :

एक्सपो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टावर, 26 राजिन्द्रा प्लेस
नई दिल्ली-110 008

REFRIGERATORS
DEEP FREEZERS

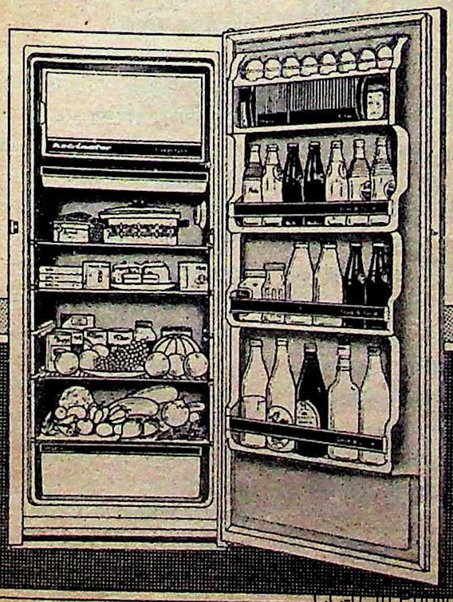

केल्विनेटर
रेफ्रिजरेटर
"इसकी ठण्डक... बेमिसाल!"

Mutual-4711 D/d HN

करुणानिधि को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी !

आंध्र के मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष एनटी रामाराव ने पिछले दिनों दिल्ली में अपनी तरफ से यह फैसला कर लिया कि अगर आगामी चुनाव के बाद केंद्र में मोर्चे की सरकार बनती है, तो उसके भावी राष्ट्रपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि होंगे। वीपी सिंह ने भी इसे स्वीकार ही कर लिया है। करुणानिधि इस सुझाव को सुनकर मात्र मुस्कराये ही नहीं, बल्कि जब उनकी कार दिल्ली के नार्थ-साउथ ब्लाक के बीच से निकली, तो उन्होंने बहुत हसरत भरी नजरों से राष्ट्रपति भवन को देखा भी। वैसे अभी वर्तमान राष्ट्रपति वेंकटरमण के कार्यकाल के करीब चार साल बाकी हैं। दरअसल, दिल्ली के आंध्र भवन में पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि का सभी गैरइंका दलों की तरफ से जब शानदार स्वागत किया गया था, तो उसी समय अनौपचारिक बातचीत के दौरान एनटीआर ने बहुत गंभीरता से तमिल में कहा, "करुणानिधिजी, अब आपको देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद लेने के लिए तैयार होना होगा। जब दिल्ली में हमारी सरकार होगी, तो आप राष्ट्रपति भवन में बैठकर हम लोगों का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का मार्गदर्शन करेंगे।" इस पर वीपी सिंह ने सिर हिलाकर समर्थन किया। करुणानिधि इस बात पर केवल मुस्करा दिये।

एनटीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। उनको पूरे देश में घुमाकर उनकी अखिल भारतीय छवि बनायी जायेगी। लेकिन करुणानिधि का कहना है कि वे फिलहाल तमिलनाडु नहीं छोड़ पायेंगे, क्योंकि वहां उनको काफी समस्याओं से अभी जूझना है। ऐसा लगता है कि करीब छह महीने बाद करुणानिधि का देशव्यापी दौरा आयोजित किया जायेगा, लेकिन इसके लिए उनकी एक शर्त है कि वे अपना भाषण तमिल में ही देंगे। इसे चौधरी देवीलाल तक ने स्वीकार कर लिया है। देवीलाल का कहना था कि यह देश बहुत उदार है। पूरा देश इसे खुले दिल से स्वीकार करेगा। अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाएं अगर देश में अपना महत्व जमा लें, तो हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

गुलाम नबी आजाद उवाच

दिल्ली दरबार के एक खास सिपहसालार, जिन्हें आम दरबारी 'गुलाम' और 'आजाद' दोनों नामों से संबोधित करते हैं, ने १० फरवरी को लखनऊ में आयोजित इंका महाधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं को जो डांट पिलायी, उससे अब इंकाइयों में खासा बवाल खड़ा हो गया है। इंका के एक विधायक सुरेंद्र अवस्थी तो खुले आम यह कहते घूम रहे हैं कि गुलाम की बात सुनने के बाद भी हम सब 'नपुंसक' बने हुए हैं। इसके जवाब में एक राज्यमंत्री ओमप्रकाश रिछारिया ने कहा कि अगर विधायक नपुंसक हैं, तो हम महानपुंसक, क्योंकि विधायक के कुछ बोलने पर उसे अगले चुनाव में—यानी एक साल बाद—पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारा मंत्री पद तत्काल छिन जायेगा। शायद यही वजह है कि गुलाम नबी आजाद की डांट खाकर भी यूपी के इंकाइयों में एमपी के इंकाइयों की तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है।

इंका महाधिवेशन में जैसे ही गुलाम नबी आजाद बोलने के लिए खड़े हुए, तमाम कार्यकर्ता 'राजीव गांधी जिंदाबाद', 'एनडी तिवारी जिंदाबाद' के नारे लगाने लगे। इस पर आजाद ने हेड मास्टरी वाले अंदाज में डांट पिलायी, "चोप्प, मैं कहता हूं चोप्प रहिए। इस तरह के नारे लगाने की जरूरत नहीं है।"

गुलाम नबी आजाद की इस डांट से मंच पर बैठे राजीव गांधी तक सकपका गये। क्योंकि कुछ देर पूर्व ही एनडी तिवारी ने अपने भाषण में सामने बैठे कार्यकर्ताओं को पार्टी की शक्तिशाली फौज बताते हुए यहां तक कह दिया था, "यही कार्यकर्ता विपक्ष के नापाक गठबंधन को एक साल के अन्दर उखाड़ फेकेंगे।"

आजाद ने जब राजीव गांधी की सकपकाहट देखी, तो वे उनकी ओर मुखातिब होकर बोले, "यह उत्तर प्रदेश है। यहां के लोग ऐसी ही भाषा के आदी हैं। मैं जब भी यहां आता हूं, इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता हूं।" राजीव गांधी ने जब ऐसे ही सलाहकार पाल रखे हैं, तो फिर विपक्ष को कुछ करने की जरूरत ही क्या है?

शपथ दिलाने का चक्कर

उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुए स्थानीय निकाय चुनाव में कई नामी-गिरामी लोग जिला परिषद और नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गये हैं। ऐसे ही एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति जवाहर लाल जायसवाल, बाबा भोले की नगरी काशी के जिला परिषद अध्यक्ष पद पर चुने गये हैं। जायसवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के जाने-माने शराब के ठेकेदार हैं। वाराणसी के आबकारी ठेकों पर उनका एकछत्र राज्य है। उनको जिलापरिषद अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण कराते समय घटी घटना ने प्रदेश में अच्छा-खासा तूल पकड़ लिया है।

नियम और परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कोई शीर्ष अधिकारी अपने पद पर रहते हुए किसी भी नवनिर्वाचित मंत्री या सदस्य को शपथ दिलाते हैं, तो शिष्टाचार के नाते शपथ ग्रहणकर्ता और शपथ दिलाने वाले दोनों को खड़े होना पड़ता है। चूंकि जिलाधिकारी जिला परिषद का अधिकारी भी होता है, अतः जिला परिषद अध्यक्ष को शपथ वही दिलाता है। वाराणसी में जब जवाहरलाल जायसवाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का अवसर आया, तो जिलाधिकारी को बड़ा बुरा लगा।

दरअसल, जब शराब के ठेकों की नीलामी होती है, तो जिलाधिकारी को ही बोली स्वीकारने या नकारने का अधिकार होता है। इसी कारण शराब के ठेकों की नीलामी के दौरान ठेकेदार उसके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। जिलाधिकारी के अहम को यही धक्का लगा कि जो व्यक्ति कल उसके सामने गिड़गिड़ाता था, उसे शपथ कैसे दिलायें? इससे बचने के लिए उन्होंने नया तरीका ईजाद कर लिया। शपथ दिलाते समय वह कुर्सी पर बैठे रहे और जवाहर लाल जायसंवाल खड़े होकर शपथ लेते रहे। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि जवाहर लाल जायसवाल सत्तापक्ष के न होकर विरोधी गुट के थे, इसीलिए जिलाधिकारी ने खुद बैठे रहना ही मुनासिब समझा।

शपथ ग्रहण के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। नागरिकों का कहना है कि जिला परिषद अध्यक्ष २५ लाख जनता का मुखिया है। जिलाधिकारी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। इससे जनता का अपमान हुआ है। उधर जवाहर लाल जायसवाल का कहना है कि वे प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिल कर इस घटना की शिकायत करेंगे।

जवाहर लाल जायसवाल का दावा है, "चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी प्रचारित करें, पर मैं वाराणसी का सर्वाधिक आयकर और राजस्व देने वाला व्यक्ति हूं। इस प्रकरण के बाद जिलाधिकारी अपनी सफाई देते घूम रहे हैं कि उनका मंशा ऐसा नहीं था।

जब किसी निर्णय पर सालों-साल साथ निभाने की बात निर्भर हो तो ठोस प्रमाण उसमें मदद करते हैं

प्रमाण १ : गुणवत्ता
रेमण्ड का नाम ही सर्वोच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय है.

प्रमाण २ : मज़बूती
बी आइ एस के मानकों से निश्चय ही ज़्यादा 'कॉम्प्रेसिव' शक्ति.

प्रमाण ३ : ब्लेन
महीनतम ब्लेन के कारण अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मनचाही मज़बूती की गारंटी.

प्रमाण ४ : जमाव गुण
रेमण्ड सीमेंट पूर्ण जमाव का आश्वासन देता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव की अवधि बी आइ एस मानकों से बेहतर है.

प्रमाण ५ : विक्रेताओं का जाल
देशभर में रेमण्ड के अधिकृत विक्रेताओं का जाल शत प्रतिशत असली सीमेंट उपलब्ध कराता है.

प्रमाण ६ : पैकेजिंग
स्वचालित रोटरी पैकेजिंग मशीनों द्वारा सबसे मज़बूत प्लास्टिक और जूट की बोरियों में पैक याने निकाल लिए जाने का अंदेशा ही नहीं.

प्रमाण ७ : बचत
कोई अन्य सीमेंट हर बार इतने ठोस लाभों की गारंटी दे नहीं सकते.

प्रमाण ८ : हमारे कुछ ग्राहक
एन टी पी सी, ऑयल इंडिया लि., भारतीय रेलवेज़, वायजैक्र स्टील प्लांट, ईस्ट इंडिया होटल्स लि., आइ टी सी लिमिटेड, वोल्टास लि., टाटा रोबिन्स फ्रेसर, निटको टाइल्स, अंसल हाउसिंग प्रा. लि., एस.आर.एफ. निप्पॉन डेनरो इस्पात लि. जी.ई.सी.

कैलाश सीमेंट : निर्माता

रेमण्ड

गुणवत्ता का दूसरा नाम.

पंचों का फैसला सिर-माथे पर, लेकिन

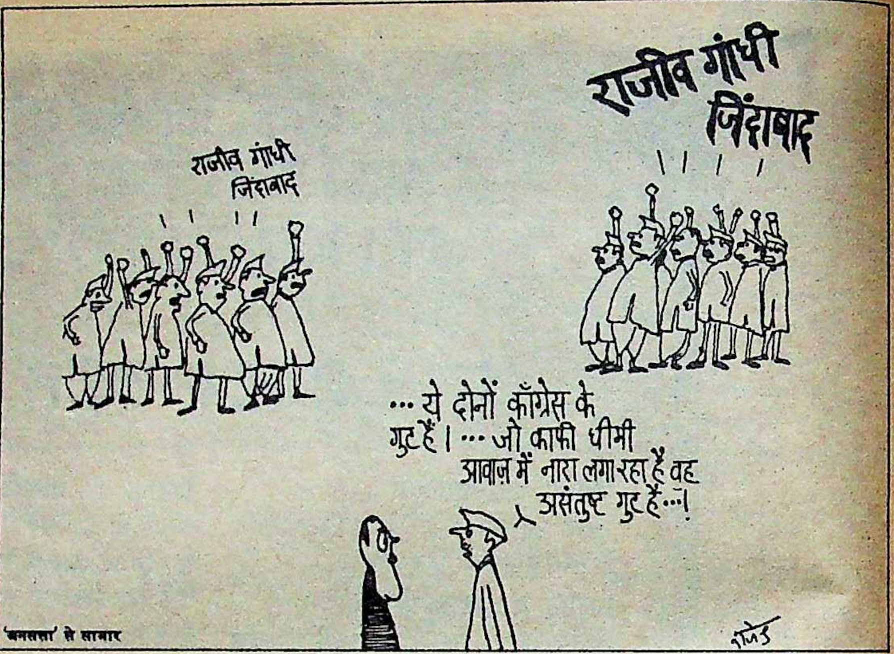
राजीव गांधी जिंदाबाद
राजीव गांधी जिंदाबाद
...ये दोनों कॉंग्रेस के गुट हैं। ...जो काफी धीमी आवाज़ में नारा लगा रहा है वह असंतुष्ट गुट है...!

'जनसत्ता' से साभार

भजनलाल की करामात ने दिल्ली दरबार को विधायकों और सांसदों की धींगामुश्ती कर रही भीड़ से काटकर 'पंचायत' में खड़ा कर दिया। बौनों में जब दरबार तन कर खड़े हुए, तो उनको अपना कद लंबा होने का अहसास हुआ। वे भजनलाल के कान में फुसफुसाये, "भजनजी, इस भीड़ में तो मेरा कद काफी ऊंचा दिख रहा है। इस भीड़ को तो मैं संभाल लूंगा न!" भजनलाल ने समदर्शी भाव से उत्तर दिया, "महाशय, संभाल तो आप उन बेलगाम इंका विधायकों और सांसदों की भीड़ को भी लेते, लेकिन उस भीड़ में आपने मुझे अपनी चमचागिरी का सुअवसर नहीं दिया। इसीलिए मैंने आपको उस भीड़ से काटकर इस भीड़ में लाने का षड्यंत्र रचा। कैसा रहा, मेरा यह षड्यंत्र हुजूर? बूटा सिंह के सीने पर सांप लोट गया होगा!" दरबार ने भजनलाल के प्रश्न का कोई उत्तर न देकर पंचायत राज सम्मेलन में आये विभिन्न वेशभूषा धारी पंचों को निहार कर अपना मनोरंजन शुरू कर दिया।

जब ज्यादा देर हो गयी, तो श्याम लाल यादव ने भजनलाल के कान में कुछ कहा। यादवजी की बात सुनते ही भजनलालजी ने अपने गोल्डन फ्रेम के चश्मे का फोकस ठीक किया, "सर, ज्यादा देर तक इन पंचों को आप न निहारें। अगर इन लोगों ने भी आपको 'पहचान' लिया, तो खेल बनने की जगह बिगड़ सकता है। वैसे इन सब को एडवांस देकर ही यहां लाया हूं।" दरबार ने बीच में ही अपने 'मनोरंजन' को कट कर, मस्तिष्क में कौंधे 'आइडिया' को भजनलाल के सामने पेश कर दिया, "देवीलालजी, मेरे मस्तिष्क में एक आइडिया आया है...।" भजनलाल को पसीना छूट गया और वे अगल-बगल झांककर देवीलाल को ढूंढ़ने लगे। इसी बीच श्याम लाल यादव ने भजनलाल के कान में बनारसी हंसी, कमलापति त्रिपाठी से माफी मांगकर, उंडेल दी, "हुजूर, अकसर जब भीड़ ज्यादा होती है, तो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। पिछली से पिछली बार हुजूर ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस कह दिया था। आपको भी भजनलाल की जगह 'देवीलाल' बोल गये। इसमें पसीना छूटने की कोई बात नहीं है, विश्नोई नरेश। दरबार तो अकसर ऐसा मजाक करते ही रहते हैं।" यादवजी की बनारसी हंसी के बाद भजनलाल की उखड़ी सांस कंट्रोल में आयी, तो उन्होंने अपने रेशमी रूमाल से पसीना पोंछते हुए कहा, "सर, देवीलाल नहीं, भजनलाल। आपका दल बदल शिरोमणि भजनलाल।" दरबार ने अपने को तुरंत सुधार लिया और पीछे खड़े मणिशंकर अय्यर को फौरन घूमकर निर्देश दिये, "देवीलाल की जगह भजनलाल रिकार्ड में कर लें।" फिर दरबार भजनलाल की तरफ मुखातिब होकर उत्साह से बोले, "हां तो देवी...अरे आपका क्या नाम है?...जो भी हो! हां, तो मेरे मस्तिष्क में यह आइडिया कौंधा है कि हम लोग इन पंचों की भीड़ को 'अपना उत्सव' में शामिल कर सकते हैं। इससे हमको दोहरा फायदा भी हो सकता है। एक ओर 'अपना उत्सव' में नयी जान आ जायेगी, दूसरी ओर चुनाव में ये लोग हमारी मदद कर सकेंगे।" भजनलाल ने दरबार के सुझाव पर अपनी पूरी बत्तीसी बाहर निकाल ली, "सर, मैं समझता था कि ओरिजिनल आइडिया केवल विश्नोई के भेजे में ही गिरते हैं। लेकिन आज वह भ्रम टूट गया। सर, आप तो ओरिजिनल आइडियों की खान हैं। बस, उनको कार्य में बदलने वाले मेरे जैसे आपको नहीं मिले, अन्यथा आपको यह दुर्दिन...।" दरबार ने फिर बात काट दी, "हां तो, इन पंचों को क्या देना है। आपने एडवांस तो कर ही दिया है।" भजनलाल ने दरबार के कान में फूंक मारी, "सर, इनको लंबे-लंबे आश्वासन देने हैं। इनको अपना माई-बाप कहना है।" दरबार भड़क उठा, "देवी...ओ आई एम सारी...मिस्टर भजनलाल। इनको लंबे-लंबे एश्योरेंस तो मैं दे सकता हूं। लेकिन माई-बाप नहीं बोल सकता। मेरे 'इनलाज' को इसमें परेशानी हो सकती है।" भजनलाल की जब कुछ समझ में नहीं आया, तो वे बगलें झांकने लगे। पीछे ऊंघ रहे शंकरानंद को झकझोर दिया, "यह कौन सा 'ला' तुमने बना दिया है, जिससे हुजूर को माई-बाप कहने में परेशानी हो रही है।" कानूनमंत्री शंकरानंद ने भौंचक्के होकर कहा, "भजनलालजी, दरबार के लिए भी क्या कोई 'ला' बना सकता है। वे तो अपने आप में पूरे 'ला' हैं। बोफोर्स तोप की संसदीय कमेटी में मैंने तो यह बात साफ-साफ कह दी कि हुजूर 'ला' के घेरे में नहीं आते हैं। अरे, उसी के बाद तो मैं कानूनमंत्री बन पाया।"

जब भजनलालजी शंकरानंद के उत्तर से संतुष्ट न हो पाये, तो फिर रक्षा के लिए श्यामलाल यादव उनके कान में आ गिरे, 'इनलाज' यानी ससुराल की बात कर रहे हैं हुजूर। आपसे मैंने कितनी बार कहा कि 'रैपिड इंगलिश कोर्स' की किताब लेकर रट्टा मार लीजिये। लेकिन देवीलाल से निपटने के चक्कर में आप इसे हमेशा टाल जाते हैं। दरबार में चमचागिरी की पहली शर्त 'अंग्रेजी' है।"

भजनलाल ने श्याम लाल यादव को डपट दिया, "पैजामे में रहो यादवजी। जानने को मैं अंग्रेजी ही क्यों, दुनिया की बहुत सी भाषाएं जानता हूं। लेकिन मैं विशुद्ध विश्नोई हूं। इसलिए मुझे इन मांसाहारी भाषाओं से परहेज है।" श्याम लालजी फटकार सुनकर तुरंत दुबक गये। भजनलालजी 'इनलाज' की ऊहापोह से उभर कर फिर दरबार से चिपक लिये, "सर, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। बिलकुल मत कहिये, इनको माई-बाप। ये तो आपके गुलाम हैं। बस, उनको बीडीओ, एडीओ, पंचायत सेवकों पर रौब गांठने के लिए थोड़ा-सा 'पावर' दे दीजिए और सैर-सपाटे के लिए थोड़ी-सी 'रकम'। अपने विधायकों और सांसदों को धता बता दीजिए और इनसे नाता जोड़िए। उनकी तुलना में इनकी डिमांड हमेशा कम ही रहेगी।" दरबार के मस्तिष्क में भजनलाली फार्मूला तेजी से उभरने लगा कि पीछे से शोर और आपाधापी शुरू हो गयी। दरबार ने कौतूहल से पूछा कि 'मेरी नाक में यह सड़ांध क्यों आ रही है? लपककर जार्ज ने दरबार के कान में बताया, "सर, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि-अनादि प्रदेशों से असंतुष्ट विधायक इस पंचायत राज सम्मेलन में आ धमके हैं और हो-हल्ला कर रहे हैं कि पंचायतों पंर से उनकी हुकूमत को खतम न किया जाये। दरबार ऐसा करके उनके कद को कम करने की चाल चल रहा है।" जार्ज की बात को आगे मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाया, "सर, विधायकों की तो परेशानी समझ में आती है, लेकिन आपके सांसद भी बहुत नाराज हो रहे हैं। कह रहे हैं कि अब दरबार में इन गांव के पंचों का डेरा होगा, तो वे क्या भाड़ झोंकेंगे। वे लोग भजनलाल को 'भज' लेने की कसमें खा रहे हैं।" कोई और कारिंदा आगे बोले कि उसके पहले भजनलाल भड़क उठे, "अरे भजनलाल को भजनेवाले अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अगर हुजूर, उस देवीलाल से (बंसीलाल की जगह) मुझे पिछले चुनाव में भिड़ा देते, तो मैं उसे भी 'भज' लेता। लेकिन हुजूर के चमचों ने मेरा ही नहीं, उनका भी बंटाढार कर दिया। मैं उसे (देवीलाल) उसी समय खतम कर देता, तो आज वह 'अजगर' बनकर फुंकारे न मारता।" दरबार ने भजनलाल को शांत रहने का इशारा किया, तो पीछे दुबके श्याम लाल यादव हाथ में पानी का लोटा लिये हुए उभर आये, "भजनलालजी, पानी शीतल है। गले से नीचे उतारें, आत्मा और परमात्मा दोनों को शांति मिलेगी।" भजनलालजी ने यादवजी के डायलाग पर कोई ध्यान न देकर विशुद्ध शीतल जल पेट में उतारना शुरू कर दिया। इतने में दरबार 'पंचों' के बीच होने के लिए आगे बढ़ लिये। कोने में खड़े उत्तर प्रदेश के नयी दिल्ली तिवारी ने लपक कर दरबार के कान में कहा, "श्रीमन पंचों को अगर आपने अपने कब्जे में ले लिया, तो देश में जम्हूरियत बहुत मजबूत हो जायेगी। मैंने पिछले दिनों पंचायत चुनाव इसी मकसद से ही कराये थे कि आपका ध्यान प्रजातंत्र की इस छोटी इकाई की ओर खींच सकूं। अब अगर इसके लिए कोष बन जाये तो...।" पास खड़े वीरू उस्ताद ने गुस्से में आकर नयी दिल्ली तिवारी के सिर पर अपना टेलीफोन का रिसीवर दे मारा, "मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप यह कोष बनाने की पट्टी दरबार को क्यों पढ़ा रहे हैं? यह कोष मेरा आधार खतम करने के लिए बनाया जायेगा। लेकिन मैं यह कोष कतई नहीं बनने दूंगा। जब मैं फिर से उप्र पहुंच जाऊंगा तब ही यह कोष बनेगा।" तिवारीजी जब तक सिर पर पड़ी मार को सहलायें कि उसके पहले श्याम लाल यादव ने लपक कर वीरू उस्ताद से आहिस्ता से पूछ लिया, "क्या तुम यूपी जाने वाले हो? दिल्ली दरबार क्या तुमको फिर से यूपी भेजने को राजी हो गया है?" वीरू उस्ताद हल्का-सा मुस्करा कर बोले, "श्याम लालजी, यूपी जाऊंगा या नहीं, यह तो मुझे पता नहीं। लेकिन समय-समय पर मैं उड़ाता तो यही रहता हूं कि बस, एक-दो हफ्तों में यूपी गया। इस अफवाह से यूपी के अफसर, मंत्री-विधायक मेरे आगे-पीछे घूमा करते हैं। माहौल बनाये रखने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाते रहना बहुत जरूरी होता है।" श्याम लालजी एक ठंडी सांस लेकर फिर से भजनलालजी के पीछे आ गये, "दूसरा लोटा पानी लाऊं।" भजनलालजी ने खाली लोटा श्याम लालजी को थमाते हुए झिड़क दिया, "श्याम लालजी, मुझे ज्यादा पानी पिलाने की कोशिश मत करना। बड़े-बड़ों को मैं पानी पिला चुका हूं।" भजनलालजी उसके बाद तेजी से दरबार की तरफ बढ़ गये, "सर, आप अब जिन पंचायती लोगों को अपने घेरे में लेने जा रहे हैं, वे होते हैं बड़े चालू। इनको तो आप कचालू बनाकर ही कब्जे में कर सकते हैं।" दिल्ली दरबार ने 'पंचों' से मिलते हुए कनखियों के जरिये भजनलाल से पूछा, "मैंने तो वीडियो फिल्म में इन गांव के पंचों को देखा है। मुझे तो अच्छे, भोले-भाले लगे। फिर तुम इनको 'चालू-कचालू' क्यों कह रहे हो!" भजनलाल ने अपने गोल्डन फ्रेम के चश्मे का फोकस ठीक किया, "सर, इनमें एक ही मुश्किल है। जब ये पंच कोई फैसला ले लेते हैं, तो उसको सिर-माथे पर ही लगाना पड़ता है।" दिल्ली दरबार ने कड़क आवाज में भजनलाल को काट दिया, "अरे, इसमें क्या परेशानी है! भजनलालजी यह चुनावी साल है। इसमें तो सारे फैसले सिर-माथे पर ही होते हैं। और इन पंचों के फैसले तो जोर-शोर से सिर-माथे पर होंगे।" दिल्ली दरबार आगे बढ़कर पंचों से पूरी तरह घिर गये। पंचों ने अपनी-अपनी बोली में 'फैसले' सुनने शुरू कर दिये। दिल्ली दरबार ने पंचम में आकर कहा, "पंचों का फैसला सिर-माथे पर...।" पंचायत राज सम्मेलन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन जब तालियों की गड़गड़ाहट रुकी, तो पीछे से असंतुष्ट विधायकों और सांसदों का समवेत स्वर गूंज उठा, "लेकिन पनाला (दिल्ली का इमेज ग्राफ) वहीं गिरेगा।" दिल्ली दरबार ने पीछे घूमकर फिर दोहराया, "पंचों का फैसला सिर माथे पर...।" जवाब में फिर वही समवेत स्वर उभरा, "लेकिन पनाला वहीं गिरेगा।" दरबार सशंकित भाव मुद्रा में इधर-उधर देखकर बुदबुदाये, "पंचों का फैसला सिर-माथे पर।" जवाब में समवेत स्वर भी बुदबुदाया, "लेकिन पनाला वहीं गिरेगा।" भजनलालजी को कुछ समझ में नहीं आया, तो वे पंचायत राज सम्मेलन में दुबक कर हरिभजन करने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब 'पंचों का फैसला सिर-माथे पर, तो पनाला वहीं क्यों गिरेगा?"

—दरबारी लाल

'पीछे से असंतुष्ट विधायकों और सांसदों का समवेत स्वर गूंज उठा, "लेकिन पनाला (दिल्ली का इमेजग्राफ) वहीं गिरेगा।" दिल्ली दरबार ने पीछे घूमकर फिर दोहराया, "पंचों का फैसला सिर माथे पर...।" जवाब में फिर वही समवेत स्वर उभरा, "लेकिन पनाला वहीं गिरेगा।" दरबार सशंकित भाव मुद्रा में इधर-उधर देखकर बुदबुदाये, "पंचों का फैसला सिर-माथे पर।" जवाब में समवेत स्वर भी बुदबुदाया, "लेकिन पनाला वहीं गिरेगा।" भजनलालजी को समझ में नहीं आ रहा था कि जब 'पंचों का फैसला सिर-माथे पर, तो पनाला वहीं क्यों गिरेगा?'

देश

१ फरवरी : फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकाएस मितेरां भारत पहुंचे, राजीव गांधी से पहले दौर की वार्ता, भारत-फ्रांस में सहयोग बढ़ने के संकेत। फिल्म 'सलाम बाम्बे' आस्कर प्रतिस्पर्धा में शामिल।

२ फरवरी : बिहार विधानसभा भारी हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राजस्थान में भी असंतोष भड़का।

३ फरवरी : भाकपा द्वारा जनमोर्चा से तालमेल बिठाने का फैसला। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम इस वर्ष के नोबल पुरस्कार (शांति) के लिए प्रस्तावित।

४ फरवरी : असंतुष्टों से निबटने के लिए भागवत झा आजाद द्वारा पदयात्रा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत द्वारा अपने पद से इस्तीफे की पेशकश। विपक्षी नेताओं के खातों की जांच संबंधी लगे आरोप का वीपी सिंह द्वारा खंडन।

५ फरवरी : स्त्री अकाली दल प्रमुख राजिंदर कौर की हत्या। इंडियन आयल कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त।

६ फरवरी : तीर्थराज प्रयाग में सोमवती अमावस्या के मौके पर एक करोड़ लोगों द्वारा स्नान। सुविख्यात वैज्ञानिक ८० वर्षीय डा० एस भगवंतम का मद्रास में निधन। शमशेर सिंह सुरजेवाल हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नवजोत सिद्धू को सशर्त वेस्टइंडीज जाने की अनुमति।

७ फरवरी : राजीव गांधी द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यक्रमों की घोषणा। ध्रुपद कला के माहिर प्रसिद्ध गायक ५५ वर्षीय नासिर फैय्याजउद्दीन डागर का निधन।

८ फरवरी : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव द्वारा नये सिरे से पुनर्गठन हेतु मंत्रिपरिषद के ३१ मंत्री पदमुक्त। मैसूर में दूरदर्शन धारावाहिक 'टीपू सुल्तान' की शूटिंग के दौरान स्टूडियो में भीषण आग, कई मरे, संजय खान बुरी तरह जख्मी। समाचार एजेंसी यूएनआई के प्रमुख यूआर कलकूर का निधन।

९ फरवरी : बिक्री कर से संबंधित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विपक्षी मुख्यमंत्रियों व राजीव गांधी में तेज झड़प। इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा 'उत्तर रामायण' के प्रसारण पर रोक।

१० फरवरी : राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा जनता दल को मान्यता। आस्ट्रेलिया हिंद महासागर में अपने आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में भारत के फैसले पर तैयार।

११ फरवरी : जनता दल के उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े द्वारा डा० स्वामी से कानूनी नोटिस द्वारा खंडन करने का आग्रह अन्यथा दो करोड़ रुपए हर्जाने का मुकदमा दायर करने की धमकी।

१२ फरवरी : अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक के जयललिता व जानकी गुट में तालमेल। मुसलमानों के इस्माइली पंथ के प्रमुख आगा खान १३ दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे।

१३ फरवरी : श्रीनगर में हिंसा भड़की। भिंडरांवाले टाइगर फोर्स के स्वयंभू एरिया कमांडर भूपेंद्र सिंह उर्फ भिंडा की हत्या।

१४ फरवरी : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भोपाल के गैस पीड़ितों को ७०५ करोड़ रुपए मुआवजा दिये जाने का ऐतिहासिक फैसला। फिल्म उद्योग की समस्याओं के लिए उच्चस्तरीय समिति गठन।

१५ फरवरी : सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कारबाइड द्वारा मुआवजे के भुगतान की तिथि ३१ मार्च से घटाकर २३ मार्च कर दी।

◆

भागवत झा आजाद

रामकृष्ण हेगड़े

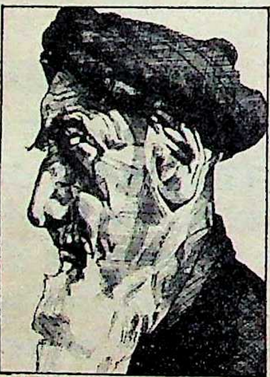

खुमैनी

सलमान रुशदी

विदेश

१ फरवरी : अमरीका द्वारा अफगानिस्तान स्थित दूतावास बंद। थाईलैंड के प्रधानमंत्री चटीछाए चुनहावन द्वारा भारत की यात्रा करने का ऐलान।

२ फरवरी : बांग्लादेश में रेल दुर्घटना, २७ मरे १०० घायल। कराची में पुनः हिंसा भड़की, कर्फ्यू लागू। पाकिस्तान में अफगानी सैन्य विमान गिरा।

३ फरवरी : बर्मा का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, ३१ मृत। सेना ने पराग्वे में ३४ वर्षों तक शासन करने वाले जनरल अल्फ्रेडो स्ट्रोसनर का तख्ता पलटा।

४ फरवरी : जनरल एंडेस रोदिग्स द्वारा पराग्वे के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ। रूसी सेना की अफगानिस्तान से वापसी शुरू। श्रीलंका ने ४१वां स्वाधीनता दिवस मनाया।

५ फरवरी : सोवियत सेना के हटते ही काबुल में मार्शल ला जैसी स्थिति। पाक द्वारा प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण। सोवियत विदेशमंत्री शेवरनादजे इस्लामाबाद पहुंचे, पाकिस्तानी नेताओं से अफगान मसले पर विस्तृत बातचीत। श्रीलंका की भूतपूर्व प्रधानमंत्री सिरीमावो बंद्रानायके पर बमों से हमला।

६ फरवरी : रूसी सेना की वापसी के बाद काबुल में राष्ट्रपति नजीबउल्लाह के सैनिकों ने मोर्चे संभाले।

७ फरवरी : पाकिस्तान द्वारा भारत का दोनों देशों की सीमा पर संयुक्त सुरक्षा पहरे का प्रस्ताव रद्द। कंधार (अफगानिस्तान) में सेना और मुजाहिदीन के बीच संघर्ष।

८ फरवरी : काबुल की रक्षा के लिए एहतियाती कार्रवाई के रूप में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ३५ हजार कार्यकर्ता हथियारों से लैस।

९ फरवरी : अमरीकी निजी गुप्तचर एजेंसी के अध्यक्ष हर्शमैन द्वारा भारतीय विपक्षी नेताओं के विदेशी खातों से संबंधित जांच के संबंध में इनकार। अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश द्वारा रक्षा व्यय में कमी करने के संकेत।

१० फरवरी : अफगानिस्तान में भारी खूनखराबे के आसार, विद्रोहियों द्वारा कई शहरों पर राकेट वर्षा।

११ फरवरी : पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने चीन की तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन भारत से संबंध सुधारने की बात दोहरायी।

१२ फरवरी : दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति ४६ वर्षीय एंटोनियो लोप्स फरेरा का निधन। इस्लामाबाद स्थित अमरीकी सांस्कृतिक केंद्र पर प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला, पुलिस ने गोली चलायी। श्रीलंका में तमिलों-सिंहलियों में संघर्ष तेज, ४५ सिंहली मृत।

१३ फरवरी : १६ हजार पाक सैनिक अफगान सीमा पर तैनात। सिंहली उग्रवादियों ने तमिल विरोधी अभियान तेज किया।

१४ फरवरी : ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी द्वारा 'सैटेनिक वर्सेज' के लेखक सलमान रुशदी की हत्या का फैसला, रुशदी द्वारा ब्रिटेन की स्पेशल ब्रांच पुलिस से सहायता की मांग।

१५ फरवरी : सोवियत सेना के आखिरी दस्ते ने अफगानिस्तान छोड़ा। लेबनान में सत्ता के लिए सेना और ईसाई छापामारों में संघर्ष, ४० मृत। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में भारी मतदान, हिंसक घटनाओं में ६५ मृत।

◆

सोवियत रूस से २० लाख जर्मनों की वापसी

३५ साल की दीर्घ-प्रतीक्षा के बाद सोवियत रूस से स्वदेश आयीं जर्मन मूल की ९२ वर्षीय इल्लियाना केज, जिनके पूर्वज २६० साल पहले रूस जा बसे थे।

पश्चिम जर्मनी के हनोवर विमान तल पर उस दिन ऐसा अभूतपूर्व भावुक दृश्य था, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। सोवियत रूस के एयरोफ्लोत विमान से उतरे २७२ यात्री जैसे ही विमानतल के स्वागत कक्ष में घुसे, उन्हें वहां खड़े उनके परिजनों ने अपनी बाहों में भर लिया। औरत, मर्द सभी इतने भावविह्वल थे कि खुशी के मारे रो पड़े थे। वे बच्चों को बेतहाशा चूम रहे थे और दुनिया के आठवें आश्चर्य की तरह सब एक दूसरे से मिल रहे थे। वास्तव में सोवियत रूस से आये जर्मन मूल के ये असाधारण यात्री वर्षों बाद नहीं, पीढ़ियों बाद अपनी मातृभूमि में वापस लौटे थे। वे बीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में घटित हो रही एक महान घटना की एक छोटी सी कड़ी थे। ढाई सौ साल पहले कैथरीन द ग्रेट के जमाने में उनके पूर्वज खेती-किसानी करने के लिए सोवियत रूस में जा बसे थे और आज इनकी संख्या वहां करीब २० लाख हो गयी है। १९१७ की महान सोवियत क्रांति के बाद से ही उनका संबंध अपनी मातृभूमि से टूट गया था और द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से ही वे स्वदेश लौटने की प्रतीक्षा में थे। रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचेव की नयी नीतियों के कारण अब जर्मन मूल के २० लाख रूसियों का स्वदेश लौटना संभव हो रहा है। इनके लिए वक्त ठहर गया था और एक मायने में इनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध १९४१ में नहीं, १९८८ में समाप्त हुआ है।

उस दिन हनोवर विमानतल पर उतरे जर्मन मूल के २७२ यात्रियों के कुछ परिजन एयरफ्लोत की पूर्व उड़ानों से पहले ही पश्चिम जर्मनी पहुंच चुके थे और आज अपने परिवार के अन्य सदस्यों का स्वागत करने के लिए हनोवर विमानतल पर उपस्थित थे। एक मास पूर्व स्वदेश लौटे वासन्ना और कार्ल हर्मन दंपती अपने पुत्र हेलोत के परिवार की अगवानी करने वहां पहुंचे थे, तो वहां एक

टैक्सी ड्राइवर डेविड रित्तर भी उपस्थित था जो अपने चचेरे भाइयों को लेने आया था, लेकिन न तो वह उनसे पहले कभी मिला था और न ही उनके चित्र ही उसने देखे थे, उसे सिर्फ उनके नामभर ज्ञात थे। जब उससे पूछा गया कि वह अपने चचेरे भाइयों को कैसे पहचानेगा, तो उसका मासूम उत्तर था, "आनेवालों में जिनकी अगवानी करता कोई नजर नहीं आयेगा, मैं उन्हीं से अपने चचेरे भाइयों के नाम पूछूंगा।" डेविड रित्तर को तो अपने भाई मिल गये, लेकिन चाकलेट, बेबीफूड और फूलों से भरी ट्राली लेकर अपनी बहन और बहन के बच्चों की अगवानी करने पहुंची केटारिना को निराश लौटना पड़ा। अब वह दो दिन बाद रूस से आनेवाली उड़ान में जर्मन मूल के लोगों में अपनी बहन के परिवार की तलाश करेगी। वह परेशान जरूर थी, लेकिन निराश नहीं। दो दिनों की और प्रतीक्षा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए पीढ़ियों तक प्रतीक्षा की है।

इन यात्रियों में ९७ वर्षीय जोहान इलियानोव बैंज भी शामिल थे। उनके परिवार की चार पीढ़ियों के २७ सदस्य तो जर्मनी पहुंच गये हैं, लेकिन अभी ३६ सदस्य सोवियत रूस में लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैंज १९१७ की सोवियत क्रांति में २७ वर्ष के थे और उन्होंने भी कामरेड बैंज के रूप में क्रांति में हिस्सा लिया था, लेकिन आज ७१ साल बाद जर्मनी लौटने पर पूंजी के नाम पर उन्हें रूसियों ने सिर्फ २५ पौंड (करीब ६२५ रुपए) अपने साथ लाने की अनुमति दी है। अब वे बेकार हैं और प० जर्मनी के फ्राइडलैंड स्थित कैंप में अगले आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बैंज की कहानी सोवियत रूस से लौटनेवाले जर्मन मूल के प्रायः हर आदमी की कहानी है। १८वीं सदी में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट जर्मनों की कृषि योग्यता से इतनी प्रभावित हुई थीं कि उन्होंने हजारों जर्मन किसानों को रूस के वोल्गा क्षेत्र में बसने के लिए उत्साहित किया था। सोवियत रूस में जाने के बावजूद इन जर्मनों ने अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को रूसी प्रभाव से महफूज ही नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि से सतत् संपर्क भी बनाये रखा। जारशाही के जमाने में जर्मन मूल के इन लोगों के हालात काफी ठीक-ठाक थे। १९१७ की सोवियत क्रांति के बाद जहां इनका अपनी मातृभूमि से संबंध समाप्त हो गया, वहीं द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर द्वारा सोवियत रूस पर हमला किये जाने के बाद जर्मन मूल के इन रूसियों को ही सर्वाधिक दुर्दशा का शिकार होना पड़ा। उन्हें वोल्गा उक्राइन, साइबेरिया और ताशकंद के श्रमिक शिविरों में हाड़तोड़ मेहनत करते हुए भटकना पड़ा। लेकिन अपनी मातृभूमि में स्थित अपने परिजनों की उन्हें खतोकिताबत न होने के बावजूद हिटलर के कारण जानकारी रही। हिटलर

कुटुंब में चिर प्रतीक्षित वापसी : पौत्र-प्रपौत्रों के बीच दादी मां

९७ वर्षीय जोहान वैंज की चार पीढ़ियों के २७ सदस्य तो वापस आ गये हैं, लेकिन ३६ सदस्य अभी भी रूस से आने की प्रतीक्षा में हैं।

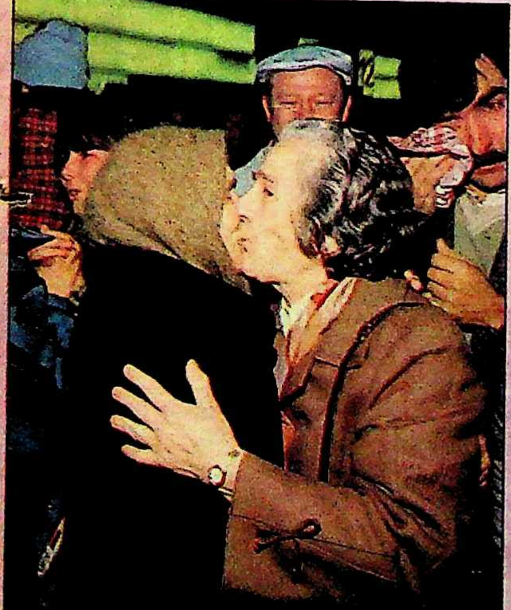

पहली बार : अनजाने परिजनों का मार्मिक स्वागत

ने सोवियत रूस स्थित जर्मन मूल के इन लोगों की और इनकी वंशावली की बृहत सूची तैयार करवायी थी जो आज जर्मन मूल के रूसियों की शिनाख्त करने में सहायक हो रही है, लेकिन सोवियत रूस में पीढ़ियां गुजार देने के बावजूद आज ये लोग खाली हाथ स्वदेश लौट रहे हैं। अभी तो जर्मन मूल के कुछ हजार ही लोग रूस से लौटे हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में ऐसे लाखों लोगों का रेला पश्चिम जर्मनी पहुंचना शुरू हो जायेगा। इन्हें रहने के लिए आवास और जीविकोपार्जन के लिए रोजगार देने की एक महान चुनौती पश्चिम जर्मनी की सरकार के सामने है। २० लाख लोगों का पुनर्वास कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, लेकिन पश्चिम जर्मनी की सरकार की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा कारणों से भी है। उन्हें आशंका है कि सोवियत रूस स्वदेश आ रहे इन जर्मन मूल के रूसियों में अपने जासूस स्थापित कर सकता है। बहरहाल, पूरी दुनिया की निगाहें पश्चिम जर्मनी पर टिकी हुई हैं। देखना है कि आर्थिक दबावों से ग्रस्त पश्चिम जर्मनी की सरकार पीढ़ियों पहले परदेसी हो चुके अपने भाई-बंदों का पुनर्वास कैसे करती है ?

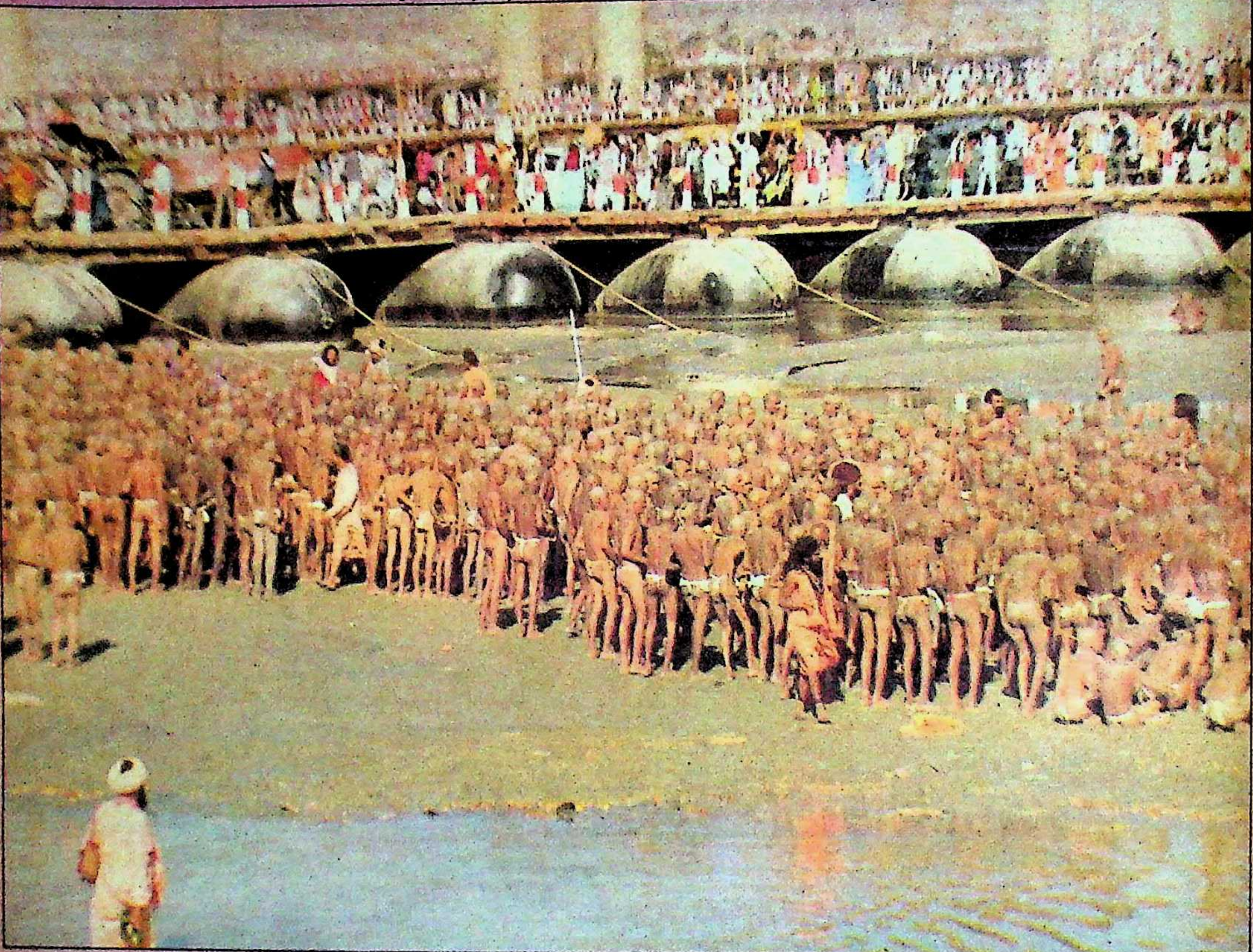

छाया: राजेंद्र कुमार

महाकुंभ १९८९ में कहां तो अंदाजा लगाया गया था कि ५-६ लाख कल्पवासी प्रयाग के संगम क्षेत्र में १४ जनवरी (मकर संक्रांति) से लेकर ६ मार्च (शिवरात्रि) तक कल्पवास करेंगे और इस दौरान मुख्य स्नानपर्वों को मिलाकर करीब तीन करोड़ तीर्थयात्री संगम क्षेत्र में आयेंगे—इसी हिसाब से सरकार ने ९० करोड़ से अधिक रुपए तैयारियों पर खर्च किये, दुकानदारों ने ऊंची-से-ऊंची बोलियां बोलकर दुकानें लीं और लाखों ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाखों रुपयों का सामान अपनी दुकानों में सजा दिया। धर्मगुरुओं, मंडलेश्वरों, अखाड़ों, तांत्रिकों, शंकराचार्यों और धार्मिक संस्थाओं ने करोड़ों भक्तों की उम्मीद में लाखों रुपए खर्च करके बड़ी सजधज के साथ अपने खेमे गाड़े, तो तीर्थपुरोहितों ने भी लाखों यजमानों की उम्मीद में काफी तैयारियां की थीं, लेकिन ये सभी निराश हुए। ५-६ लाख कल्पवासी संगम क्षेत्र में नहीं रहे और मौनी अमावस्या का महास्नान करने आयी करीब डेढ़ करोड़ की भीड़ ने इनकी ओर देखा तक नहीं। वे जैसे आये थे, वैसे ही चुपचाप गंगा व संगम स्नान करके चले गये। दुनिया का सबसे बड़ा कहा जानेवाला धार्मिक मेला फिर सन्नाटे में आ गया, लेकिन शंकराचार्यों, धर्मगुरुओं और अखाड़ों के पण्डालों में धार्मिक प्रवचनों के साथ-साथ नये साधुओं को दीक्षा देने का काम भी निर्बाध गति से चलता रहा। हर कुंभ और अर्धकुंभ में हर धार्मिक पीठ अपने संप्रदाय में नये भक्तों की भरती करता है। इसी तरह अखाड़ों में नये लोगों को नागा संन्यासी बनाया जाता है। अखाड़ों को उम्मीद थी कि हजारों की संख्या में नये नागा संन्यासी मिलेंगे, लेकिन नंग-धड़ंग रहकर कठोर साधना के निमित्त नागा संन्यासी बनने के लिए सिर्फ २०० लोगों ने ही अपने को प्रस्तुत किया। उक्त चित्र में विधिवत दीक्षा लेकर नागा संन्यासी बने कुछ वीतरागी लोग :

नौकरशाही : राजनीति के भंवर जाल में

भारत की नौकरशाही पर राजनेताओं, खासकर सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण क्या हैं ? यदि यही सिलसिला जारी रहा, तो इसका अंजाम क्या होगा ?

वैसे तो यह बात श्रीमती गांधी के शासनकाल की है, जब अंग्रेजी साप्ताहिक 'करेंट' ने अपने गपशप कालम में यह छापा था कि फलां उच्चपद पर फलां व्यक्ति की नियुक्ति के पीछे प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के एक करीबी सहायक का हाथ था। स्थिति यह हो गयी थी कि श्रीमती गांधी खबर पढ़कर आगबबूला हो उठी थीं और उन्होंने यह जानना चाहा था कि उक्त खबर अखबार तक किसने पहुंचायी ? कुछ दिनों के बाद पता चला था कि गृह मंत्रालय के एक उपसचिव ने बात-बात में अपने एक पत्रकार मित्र से वह बात कही थी, जिसके माध्यम से उस राज ने खबर का रूप ले लिया। नतीजतन बतौर सजा उक्त अधिकारी का तबादला उसके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में एक साधारण विभाग में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पद पर कर दिया गया था, क्योंकि वह दौर संजय गांधी के उदय का था और देश में आपातकाल लागू था। स्थिति इतनी बदतर थी कि राजनीतिज्ञों का नौकरशाही पर से विश्वास लगभग उठ गया था और सबको संदेह की नजर से देखा जाता था। इसलिए उस दौरान यदि किसी से मामूली-सी भूल भी होती थी, तो नागरिक सेवाओं के नियम-कानूनों को ताक पर रखकर कार्रवाई की जाती थी।

श्रीमती गांधी के काल के बाद भी राजनीतिज्ञों और देश की नौकरशाही के बीच बनी दरार मिटी नहीं। स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे नौकरशाही को पाक-साफ और संदेहों से परे रखने का सिद्धांत महज कागजी रह गया है, क्योंकि उस पर अमल करना देश के राजनीतिज्ञ पसंद नहीं करते। कहावत है कि तैरने वाला यदि बहाव के रुख से अज्ञात हो, तो नाश की ओर बढ़ता है। इसी का ध्यान रखते हुए देश की नौकरशाही ने भी बदलते परिवेश में अपने को 'फिट' रखने के लिए अपने अंदर परिवर्तन लाने शुरू किये हैं और इस बात को भूलने की कोशिश की जा रही है कि उनकी कुरसी तथा पद की गरिमा का भी कुछ अर्थ होता है।

राजनीतिक दबाव : हाल की ही एक घटना का जायजा लिया जाये, तो देश की नौकरशाही की स्थिति का जायजा मिल जायेगा। हुआ यों कि वित्त सचिव एस वेंकटीरमन ने सह सचिव भूरेलाल को लिखित निर्देश दे दिया कि कुछ राजनीतिज्ञों की कथित विदेशी संपत्तियों की जांच से संबंधित सूचनाएं डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी को दे दें। मजे की बात यह है कि उसी दौरान स्वामी की ही तरह दूसरे राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी ने भी ऐसी ही जानकारी वित्त सचिव से मांगी थी। किंतु वित्त सचिव ने जेठमलानी के लिए निर्देश जारी नहीं किये। इस संबंध में शिकायती लहजे में जेठमलानी ने बताया कि उनके पत्र की 'प्राप्ति' भी भेजना वित्त सचिव ने बेहतर नहीं समझा। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है वित्त मंत्री एसबी चह्वाण या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से वेंकटीरमण को निर्देश मिला हो कि स्वामी को सूचनाएं उपलब्ध करायी जायें और राम जेठमलानी को नजरअंदाज किया जाये। कुछ भी हो, इस हादसे से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि किस तरह से सत्तारूढ़ दल

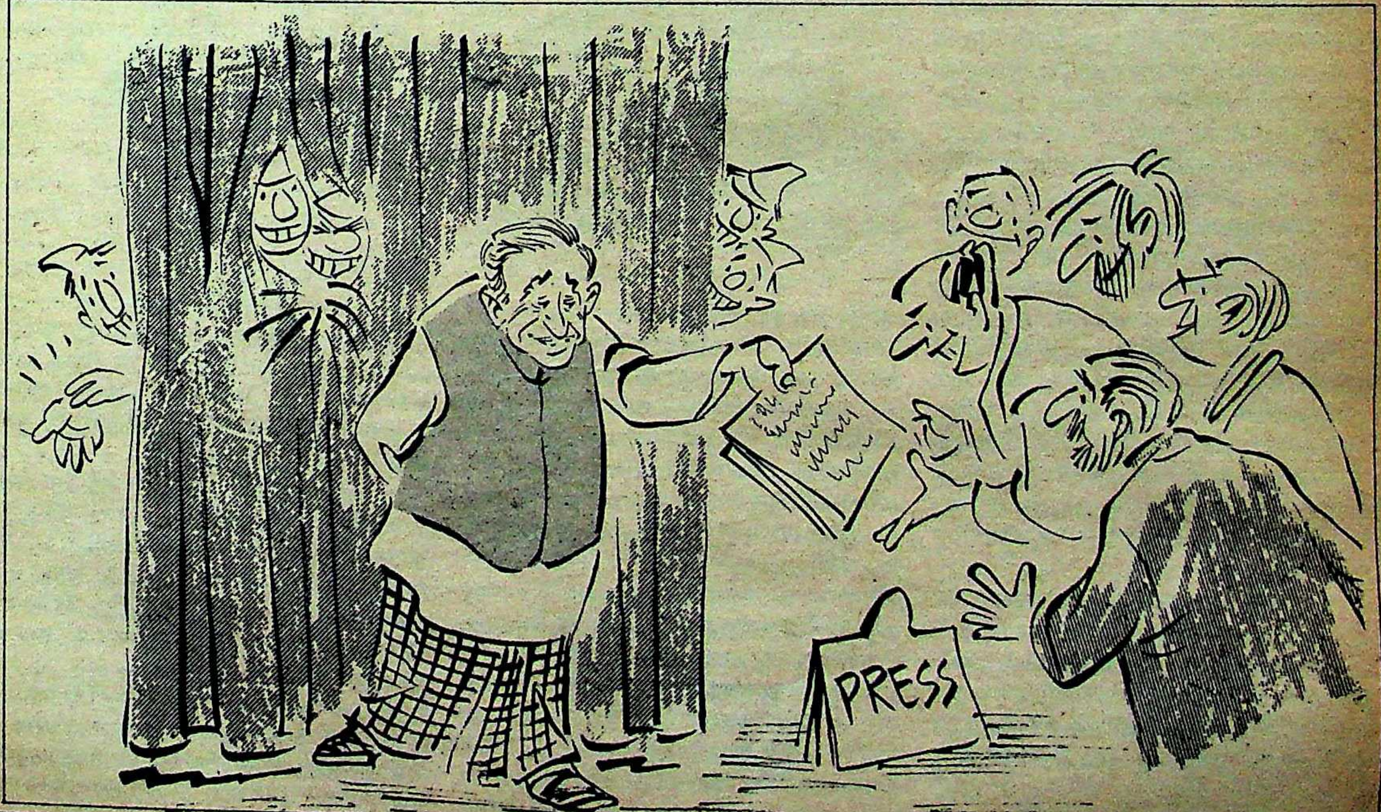

विपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए, विपक्षी असंतुष्टों का इस्तेमाल करने के लिए नौकरशाही को अनावश्यक आदेश-निर्देश देता है और नौकरशाही को मजबूर होकर उन पर अमल करना पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि स्वामी ने सूचनाएं क्यों मांगी थीं या राम जेठमलानी को सूचनाएं क्यों नहीं दी गयीं। मूल प्रश्न तो यह है कि इस तरह से राजनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए नौकरशाही का इस्तेमाल किया जाना क्या अनुचित नहीं है? इस वाकये से एक वरिष्ठ अधिकारी की छवि दागदार हो गयी, जिसकी शीघ्र ही पदोन्नति होनेवाली थी। ऐसी स्थिति में वेंकटीरमण सिवाय चुपचाप रहकर कटाक्षों को सहन करने के और क्या कर सकते हैं? जाहिर है, वे जनता को या राम जेठमलानी को तो यह बता नहीं सकते कि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया, क्योंकि उन पर राजनीतिक दबाव था।

वेंकटीरमण तो महज एक मिसाल हैं, इनके अतिरिक्त गोपीकृष्ण अरोड़ा, मणिशंकर अय्यर, बीवी कुमार और मोहन कात्रे आदि कुछ ऐसे वरिष्ठ अधिकारी और हैं, जो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री व शासक दल के हितलाभ से इतना अधिक जुड गये हैं कि किसी प्रकार का भी यदि राजनीतिक परिवर्तन हुआ, तो इनकी कुर्सियां खतरे में पड जायेंगी। किंतु इसमें इनकी क्या गलती है? बदलते परिवेश में, जिसे भी अपनी कुरसी प्यारी होगी, वह वही करेगा जो ये सब कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों के बदलते हुए मिजाज के कारण नौकरशाही का स्तर गिरता जा रहा है और दिन पर दिन राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने आम अधिकारियों की अपेक्षा अभी तक अपना स्तर बनाये रखा है। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि तालाब को प्रदूषित करने के लिए एक ही गंदी मछली काफी है।

वेंकटीरमण पर आज जो गुजर रही है, उसे वही समझ सकते हैं। एलपी सिंह, रंछोर प्रसाद या गोविंद नारायण जैसे वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी यदि चाहते, तो अपने बाद आनेवाले नये लोगों को बता सकते थे कि उन्हें किस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करके कानून और नियमों का आदर करते हुए राजनीतिक दबावों का सामना करना चाहिए, किंतु वे भी इस मौके पर खामोश रहे। वे यदि चाहते, तो वेंकटीरमण को बता सकते थे कि उसी तरह की पहली किसी घटना या कानून का सहारा लेकर स्वामी की दरख्वास्त को भी नजर-अंदाज किया जा सकता था।

इस संबंध में एडवोकेट अरुण जेटली उस दंडनीय कानून की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है, "फेरा अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार की सूचना-प्राप्ति की कोशिश पर धारा ४५ के अधीन अभियोग लगाया जा सकता है। यह सूचना देने व प्राप्त करने वाले दोनों पर लागू होगा।"

बड़ा खतरा: खैर, अब तो वेंकटीरमण को तीखी टिप्पणियां सुननी ही पड़ेंगी, किंतु इस प्रकरण से एक बात उजागर होती है कि नौकरशाही, जो स्थायी है, और विधायकी, जो अस्थायी है, दोनों के बीच संबंध कैसे और किस सीमा तक होने चाहिए। इस संबंध में केंद्र के एक सचिव ने कहा "आचरण संहिता के अनुसार, तो सांसदों को किसी अधिकारी से संपर्क नहीं स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का संपर्क अधिकारियों को उनके सही व सीधे रास्ते से भटका सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सांसद को सूचना-प्राप्ति का अधिकार नहीं है, बशर्ते वह मंत्री न हो। इस संबंध में विस्तारपूर्वक बात के दौरान उक्त सचिव ने यह भी आशंका जाहिर की कि यदि यह क्रम बना रहा, तो राजनीतिज्ञों व अधिकारियों के बीच की विभाजक रेखा धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी।

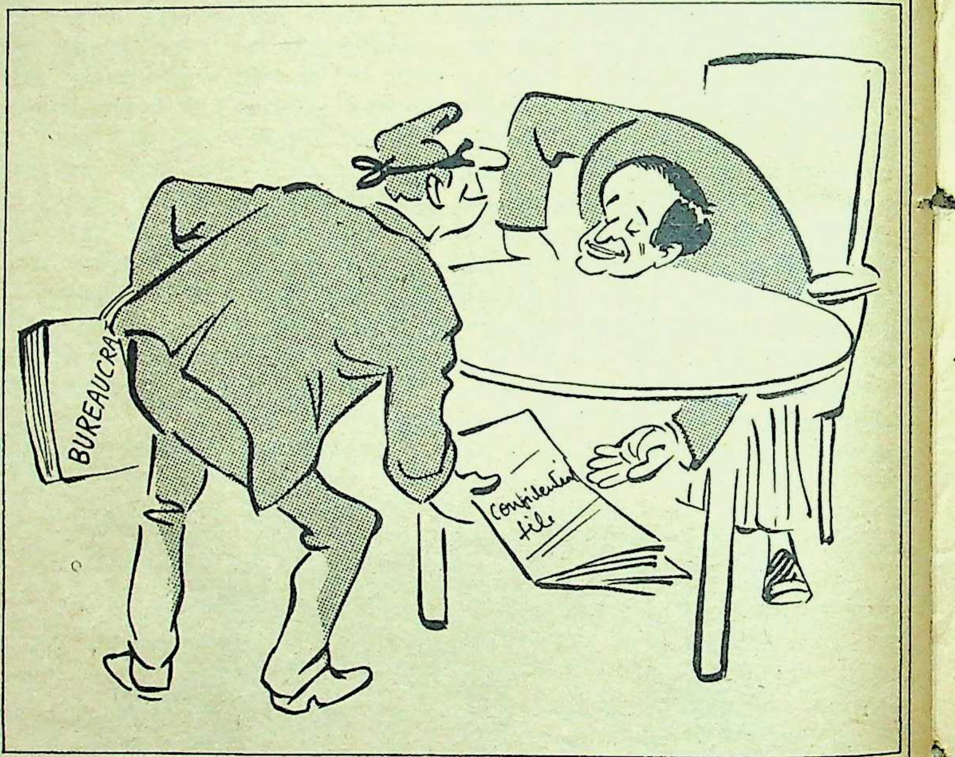

इसके विपरीत इस संबंध में एक अन्य सचिव की टिप्पणी है, "योजना आयोग के सदस्य नीति निर्धारण के समय सांसदों के अनुभवों का लाभ हासिल कर सकते हैं।" यदि यह बात मान ली जाये, तो इससे यह कहां साबित होता है कि कोई राजनीतिक दल अपने हित के लिए किसी प्रकार की भी सूचना अधिकारी से मांग सकता है? अपने अनुभवों से नौकरशाही को सहयोग देने के बजाय, राजनीतिज्ञों ने संपर्क स्थापित करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। पूर्व सूचना प्रसारण सचिव एसएस गिल इस संबंध में उस सरकारी निर्देश की ओर इशारा करते हैं, जिसके तहत सांसदों, विधायकों को सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सार्वजनिक कार्यों में उचित आदर-सम्मान व सहायता देने की बात कही गयी है। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि वे भंडाफोड़ करने में नेताओं की मदद करें। अब यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे अपनी तरक्की, अच्छी पोस्टिंग आदि के फुसलावे अथवा तबादले या राजनीतिक आका की नाराजगी के भय से कितना ऊपर उठकर तथा किस तरह अपना फर्ज निभाते हैं। गंभीर राजनीतिक मामलों में साधारणतया किसी भी अधिकारी को सांसदों से बचाने का काम मंत्री को खुद देखना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि नौकरशाही का सारा कार्य मंत्री के नाम पर ही होता है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के एक सचिव के अनुसार उनके मंत्री ने उनकी एक समय तब रक्षा की जब उन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के अपने नोट में जिक्र करने की भूल थी। उन्होंने कहा, "मंत्री ने मामले के खतम न होने तक फाइल दबाये रखी और मुझे बचा लिया।"

किंतु राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी उच्चाधिकारी को घसीटना—जैसा कि भूरेलाल से सूचना लेनेवाले डा० स्वामी के प्रकरण में सामने आया—आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। १९७७ में जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई, तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव सुशील कुमार का आंध्र में तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया गया था कि उन्होंने आपातकाल के दौरान लोगों की गिरफ्तारी के लिए सादे वारंट पर हस्ताक्षर किये थे। दुर्भाग्य से कभी-कभी ईमानदार अधिकारी भी संकट के जाल में फंस जाते हैं। भूरेलाल, जो वित्त मंत्रालय के सह

सचिव हैं, को वीपी सिंह के जाने के बाद एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट से हटाकर महत्वहीन विभाग, वित्त मंत्रालय के टकसाल विभाग में भेज दिया गया था। इसी तरह राजस्व सचिव विनोद पांडे की तो एक प्रकार से पदावनति कर दी गयी और उन्हें ग्रामीण विकास विभाग सौंप दिया गया। भूरेलाल भारत-स्विस व्यापार के भी इंचार्ज थे, किंतु उन्हें स्विटजरलैंड जाने की अनुमति तक नहीं दी गयी।

चर्चित नाम: आज दिल्ली में वातावरण ऐसा हो गया है कि उच्चाधिकारी दो श्रेणियों में विभाजित हो गये हैं। एक, जो प्रधानमंत्री व उनके सचिवालय के निकट हैं। दूसरे, जो अपनी योग्यता अथवा किसी विशेष मंत्री की कृपा से शीर्ष पदों पर हैं। प्रथम श्रेणी में आनेवाले अधिकारी के आगे-पीछे तो व्यापारी, सांसद ही नहीं, बल्कि मंत्री भी चक्कर लगाते हैं। इसके विपरीत दूसरी श्रेणी वाले उच्चाधिकारियों की कोई पूछ नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि पहली श्रेणी में आने वाले के हर अच्छे-बुरे कामों पर सबकी गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। नतीजतन वे सत्ता के गलियारों में चर्चा का अहम मुद्दा बन जाते हैं। मसलन प्रधानमंत्री के संपर्क में रहने वाले एक उच्च सचिव इस समय चर्चा के घेरे में हैं। कहा जाता है कि उक्त सचिव का बेटा ६० हजार पाउंड सालाना वेतन पर ब्रिटेन की मेरिलिच फर्म, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सलाहकार है, में कार्यरत है। यह भी कहा जा रहा है कि यह नौकरी प्रधानमंत्री के एक अन्य करीबी सचिव व उनके कुछ अन्य मित्रों के जरिये उपलब्ध करायी गयी थी। यद्यपि उक्त सचिव ईमानदारी के लिए प्रख्यात हैं, किंतु इस मुद्दे पर अत्यंत संवेदनशील हैं।

एक अन्य वरिष्ठ सचिव, जिनसे रिलायंस उद्योग के निकट संबंध बताये जाते हैं, के बंगलौर स्थित दामाद को रिलायंस के कुछ समय पूर्व जारी करोड़ों के डिबेंचर का कंप्यूटर प्रिंट आउट का काम उपलब्ध हुआ था। इसी तरह एक अन्य सचिव और उद्योगपति एलएन थापर के घनिष्ठ संबंधों की भी चर्चा गर्म है। इसी कारण कहा जाता है कि थापर के खिलाफ तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा लगाये गये फेरा कानून निरस्त कर दिये गये। दिलचस्प बात तो यह है कि ये तमाम सूचनाएं स्वयं नौकरशाहों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं में मौजूद हैं। यह कहना गलत न होगा कि नौकरशाही, जो कभी अपनी निष्पक्षता और आदर्शों के लिए प्रख्यात थी, आज ईर्ष्या और आपसी राग-द्वेष से जूझ रही है। एक उच्चस्तरीय सचिव मणिशंकर अय्यर के विरुद्ध विषवमन करता मिलता है, तो दूसरी ओर सेवानिवृत्त होने वाला एक अन्य सचिव इस बात का रोना रोता है कि चूंकि प्रधानमंत्री व उनके सचिवालय तक उसकी कोई पहुंच नहीं है, इसलिए वह किसी अच्छी पोस्टिंग से वंचित रह जायेगा।

ग्रेवाल से टक्कर: शीला दीक्षित

व्यवस्था से शिकायत: गोविंद नारायण

कुछ ऐसे भी: ऐसी स्थिति में आशा की किरण सिर्फ वही चंद अधिकारी हैं जिन्होंने ऊंचे पदों पर रहते हुए और प्रधानमंत्री के हल्कों के प्रायः करीब रहते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखी है। मिसाल के तौर पर कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख, विदेश सचिव केपीएस मेनन की छवि आज भी बेदाग है। इस कोटि में मेनन के उत्तराधिकारी एसके सिंह भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डा० स्वामी ने देशमुख के जरिये भी आवश्यक जानकारियां हासिल करने के लिए कोशिश की थी, किंतु कैबिनेट सचिव ने स्वामी को मौका ही नहीं दिया।

नौकरशाहों के राजनीतीकरण का एक अन्य संकट यह है कि चहेते नौकरशाहों व मंत्रियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। जहां शीला दीक्षित के बारे में कहा जाता है कि उनका सरला ग्रेवाल से संघर्ष चल रहा है, वहीं कुछ मंत्री मणिशंकर अय्यर की आदतों से खार खाये बैठे हैं।

पीएन हक्सर भी प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के एक अत्यधिक प्रभावशाली सचिव रह चुके हैं तथा उनसे नाराज होने वाले एकमात्र संजय गांधी ही थे। इसी तरह गोपीकृष्ण अरोड़ा जब राजीव गांधी के सर्वशक्तिशाली सह-सचिव थे, तो यद्यपि लोग उनसे डरते थे, किंतु उनकी कभी दंभी, बदतमीज आदि होने की आलोचना नहीं हुई। अरोड़ा व हक्सर द्वारा कोई निजी लाभ उठाने का भी आरोप नहीं है। यहां तक कि हाल में जब अरोड़ा के अमरीका में पढ़ रहे पुत्र को पुरस्कार प्राप्ति हेतु भारत आने की विशेष सुविधा की बात उठी, तो अरोड़ा ने उसे अस्वीकार कर दिया। किंतु ऐसे उदाहरण उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं।

संदेह होना लाजिमी: वातावरण आज इतना दूषित हो गया है कि सेवाकाल में वृद्धि के जो सामान्य नियम लागू थे, वे भी संदिग्ध हो गये हैं। हाल में सीबीआई निदेशक मोहन कात्रे, प्रधानमंत्री कार्यालय की सरला ग्रेवाल और वित्त सचिव वेंकटीरमण के सेवाकाल में वृद्धि संदेह के परे नहीं। कात्रे के ऊपर विपक्ष का जो आरोप रहा है, उसको तो राजनीतिक छींटाकशी कहा जा सकता है, किंतु आज नौकरशाह भी यह कहने से हिचकिचाते नहीं कि कात्रे ने सीबीआई को, कांग्रेस ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन में बदल दिया है और इसी कारण उनका कार्यकाल निरंतर बढ़ाया जा रहा है। वैसे सरला ग्रेवाल की दक्षता-कुशलता असंदिग्ध है। वरिष्ठ नौकरशाह उनकी योग्यता को ही कार्यकाल बढ़ाने का कारण बताते हैं और यह कि प्रधानमंत्री का उन पर पूर्ण विश्वास है। वैसे यह खबर सत्ता के गलियारों में जोर पकड़ रही है कि शीला दीक्षित व ग्रेवाल में जारी संघर्ष के कारण ग्रेवाल की जगह अरोड़ा को स्थापित किया जायेगा।

अधिकांश उच्चाधिकारियों का मानना है कि प्रशासनिक स्तर में आयी गिरावट का मुख्य कारण राजमीतिक दबाव रहा है। वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी व कर्नाटक के भूतपूर्व राज्यपाल गोविंद नारायण के अनुसार "राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का खात्मा हो जाने के बाद प्रशासन पर उसका प्रभाव लाजिमी है। वफादार नौकरशाही व भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का साथ-साथ रहना असंभव है।"

इसी तरह एसएस गिल नौकरशाहों को तीन श्रेणियों में रखते हैं। एक, हवा के रुख को पहचान कर चलने वाले वे बहुसंख्यक उच्चाधिकारी जो नौकरी की अपेक्षा स्वयं को महत्व देते हैं। दूसरे, हाथ पर हाथ रखकर बैठना श्रेयस्कर समझने वाले ऐसे उच्चाधिकारी जो स्वयं निर्णय न लेकर अपने कनिष्ठ को बलि का बकरा बनाने में हमेशा आगे रहते हैं। तीसरी और अंतिम श्रेणी में आने वाले मुट्ठी भर ऐसे कटु, कुंठित और तरक्की में पीछे रह गये लोग हैं, जिन्होंने नियम-कानून का पालन करने की चेष्टा की, किंतु जड़ और जटिल करार दिये गये। गिल का मानना है कि उनके सहयोगियों में भुक्तभोगी बहुत हैं, किंतु शहीद कोई नहीं है। उन लोगों ने स्वयं कोई संवैधानिक बलात्कार नहीं किया, किंतु उसके वे साक्षी जरूर रहे हैं।

साख बनाना जरूरी: केंद्रीय मंत्रालय

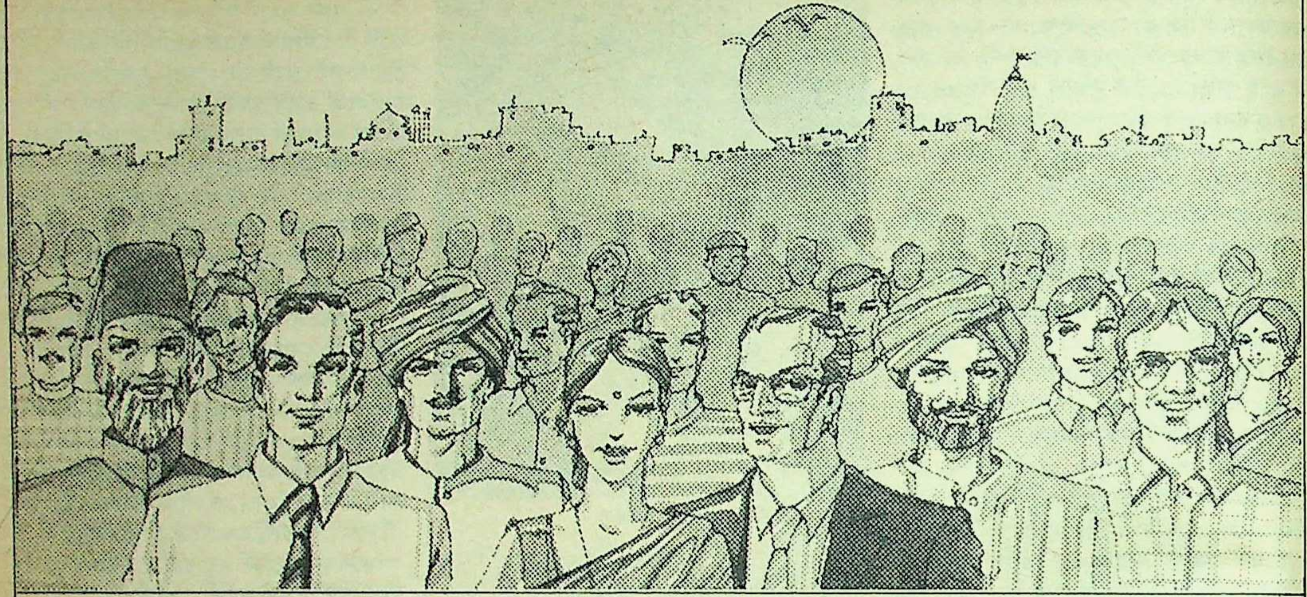

हर दिन एल आई सी 3 करोड़ रु. मूल्य के 5000 दावे निपटाते हैं।

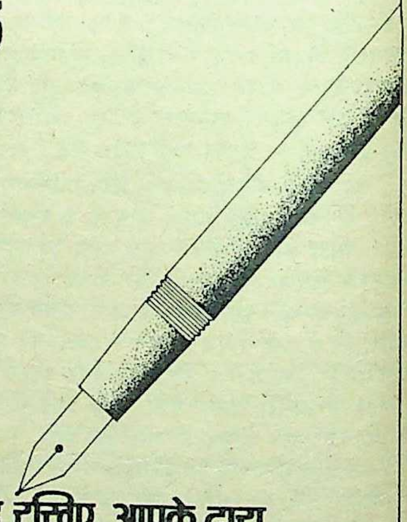

यह रहा इसका सबूत: पिछले वर्ष हमारी 1353 शाखाओं द्वारा 1000 करोड़ रु. मूल्य के 16 लाख दावे निपटाए गए।

यानी कामकाज के हर दिन 5000 दावों के लिए 3 करोड़ रु. का भुगतान।

और लगभग 60% परिपक्व दावों का भुगतान देय तारीख को या इससे पहले ही कर दिया गया।

केवल 5% से भी कम देय दावे ऐसे थे जिनका भुगतान 31 मार्च 1988 तक नहीं किया गया।

यह ऐसी कार्यकुशलता है जिसकी तुलना विकसित देशों की बीमा कंपनियों से की जा सकती है।

यही नहीं, इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आप:

- अपने पते में होनेवाले परिवर्तन के बारे में हमें सूचित करें।
- यदि आपकी पॉलिसी वेतन बचत योजना के अंतर्गत है, तो अपने कार्य-स्थान/मालिक में परिवर्तन के बारे में हमें बता दें।

याद रखिए, आपके द्वारा तुरंत उठाया गया कदम दावों को जल्द निपटाने में हमारी मदद करता है।

अधिक जानकारी और सहायता के लिए अपने एजेंट या
नजदीकी एल आई सी कार्यालय से संपर्क करें।

योगक्षेमं वहाम्यहम्

भारतीय जीवन बीमा निगम

जवाहरलाल नेहरू जन्मशती
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

R K SWAMY/LIC/3882 A/HIN

के एक सचिव ने इस संबंध में कहा, "यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या रुख अपनाते हैं और आपके सिद्धांत क्या हैं? एक बार साख बन जाने पर कोई मंत्री शायद ही, आपके पास अनुचित अनुरोध लेकर पहुंचेगा।" उन्होंने बताया कि एक बार, एक मंत्री ने किसी व्यक्ति की नौकरी लगाने को उनसे कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। गोविंद नारायण भी मानते हैं कि यह व्यक्ति-विशेष पर निर्भर करता है। वे कहते हैं, "जब मैं राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष था, तो एक मंत्री ने मुझसे एक कार उपलब्ध कराने को कहा जिससे मैंने इनकार कर दिया था।"

दरअसल आम चुनावों के करीब होने के कारण अधिकांश उच्चाधिकारी इस प्रश्न पर माथापच्ची कर रहे हैं कि वे शासक दल के हितों और कल्याणकारी राज्य की सरकार के हितों के बीच विभाजक रेखा कैसे खींचे? साथ ही, किसी नीति के खिलाफ अपनी राय जाहिर करने का उन्हें क्या अधिकार है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक भास्कर घोष ने जब शासक दल और उसके लोगों की गतिविधियों के व्यापक कवरेज (प्रदर्शन) के विरुद्ध राय जाहिर की, तो उन्हें अपने पद से हाथ धोना पडा। किसी भी उच्चाधिकारी को ऐसी स्थिति में कीमत चुकानी ही पड़ेगी कुछ भी हो, सचाई तो यही है कि नौकरशाही को सरकारी नीतियों पर अमल करना ही पड़ता है। गिल इससे सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं "किसी उच्चाधिकारी के सामने आदेशों के पालन के अलावा कोई विकल्प नहीं, बशर्ते आदेश गैरकानूनी और असंवैधानिक न हों।" किंतु इसका एक दुखद पहलू यह है कि नौकरशाही के लिए ऐसी कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं, जिसके सहारे वह गैर कानूनी आदेशों से बच सके। अधिक से अधिक वह पद त्याग कर सकता है। यह हिम्मत बिरले ही करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल आईएएस अकादमी के एक निदेशक की है, जिसने देहरादून में इसलिए इस्तीफा दे दिया, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने एक गंभीर मुद्दे पर उसके प्रस्तावो को गलत तरीके से नजरअंदाज किया था।

फेयरफैक्स मामले की जांच करने वाले ठक्कर-नटराजन आयोग और आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने वाले शाह आयोग के पास यह सुझाव देने के माकूल कारण थे कि नौकरशाह राजनीतिक आकाओं के लिखित आदेशों का ही पालन करें। किंतु इस समस्या का कुछ अंश इस तथ्य में भी निहित है कि व्यवस्था की सुरक्षा के लिए समुचित प्रावधानो का अभाव है। गोविंद नारायण के अनुसार "आज हमें जो दिखायी दे रहा है, वह समूची व्यवस्था के क्षीण होने का संकेत है। नौकरशाहों का इस्तेमाल न केवल विपक्ष के लिए, बल्कि सत्तारूढ़ दल में भी प्रतिद्वंद्वियों की काट के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बदलने के साथ होने वाले व्यापक तबादले इसी की एक कड़ी हैं।" इस समस्या का एक हल यह है कि गृह मंत्रालय ऐसा आदेश जारी करे जिसके तहत किसी अधिकारी का तबादला नियमित रूप से हो, राजनीतिक कारणों से नहीं।

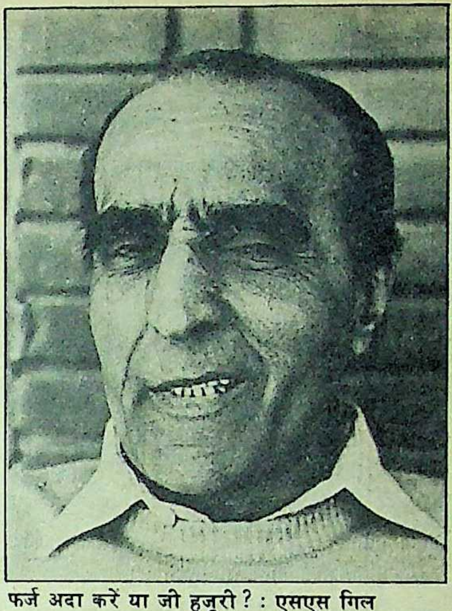
फर्ज अदा करें या जी हुजूरी?: एसएस गिल

मौका परस्त है नौकरशाही: रामजेठमलानी

राजनीतिक नौकरशाह: गोपीकृष्ण अरोड़ा

अनावश्यक हस्तक्षेप: नौकरशाही की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता में आयी आंच का एक कारण प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हथियाया गया असाधारण अधिकार है। उक्त अधिकारियों के अनुसार यह सत्ता का मूल स्रोत बन गया है। यहां तक कि एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सहसचिव ने एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को एक पत्र द्वारा निर्देश दिया था कि संसद में प्रश्नों का उत्तर वे किस प्रकार दें। इस पर मंत्री महोदय का विचलित होना स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री कार्यालय के दादागिरी रवैये को वर्तमान सरकार ने संस्थागत बना दिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जापान यात्रा, जिसका तथाकथित लक्ष्य परस्पर व्यापार-वाणिज्य का विकास करना था, के दौरान वेंकटीरमण तो गये, किंतु तत्कालीन वाणिज्य-व्यापार मंत्री एनडी तिवारी को ले जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। यह एक नौकरशाह का इस्तेमाल करके तिवारी को उनकी औकात जताने का ही भोंडा हथकंडा था।

इलाज क्या है?: कुछ असंतुष्ट तत्व उस अमरीकी प्रणाली को लागू करने का सुझाव देते हैं जिसके तहत हर नये राष्ट्रपति को २० प्रतिशत अधिकारी स्वयं चुनने का हक होता है। किंतु एक सचिव का कहना है कि भारतीय परिदृश्य में यह केवल मौजूदा जातिवाद और भाई-भतीजावाद को ही बढ़ावा देगा। अमरीका में यह प्रणाली इसलिए कारगर साबित हुई है, क्योंकि वहां व्यक्तिगत अधिकार समुचित रूप से परिभाषित हैं।

प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सुमन दुबे जैसे लोगों का यह सामान्य तर्क है कि देश की समस्त समस्याओं का मूल कारण प्रशासन का जन सामान्य से संपर्क न होना और समाजवाद की मूल भावना से रहित होना है, सही नहीं। उच्च पदों पर पहुंचने से पूर्व सभी उच्चाधिकारियों का वर्षों जनसंपर्क रहता है। अधिकांश सचिव वर्षों न केवल जिलों में काम कर चुके होते हैं, बल्कि ऐसे विभागों में भी जहां उनका संबंध समाज के विभिन्न वर्गों से निरंतर बना रहता है। सच यह है कि नौकरशाही उस घोड़े के समान है, जो अपने सवार के इशारे पर निर्भर रहता है।

आज भारतीय नौकरशाही आत्मघाती मार्ग पर अग्रसर है। मुख्यतः इसलिए क्योंकि सत्ता के शहंशाह आज उसे विभिन्न स्तरों पर इस्तेमाल करते हैं और चुनावों के दौरान उसे अभियानकर्ता और वोट बटोरनेवाली मशीनरी की शक्ल में देखना चाहते हैं। विडंबना यह है कि २१वीं शताब्दी की ओर उन्मुख समझी जा रही नौकरशाही वास्तव में ब्रिटिश काल की ओर उन्मुख है, जिसका मुख्य ध्येय जन सेवा और कुशल प्रशासन नहीं, बल्कि शासक वर्ग को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली करना था।

—पद्मा शास्त्री/सुधा भाटिया

कैमरे के सामने पहली बार.
सौ साल पहले.

लाला दीनदयाल, हैदराबाद के एल्बम से: सौ साल से भी अधिक पुरानी तस्वीर.

अपने पारिवारिक एल्बम के कुछ पन्ने पलटाकर देखिए. जिनमें सजी हैं बरसों पुरानी यादों को संजोए चंद तस्वीरें !

ब्लैक एंड व्हाइट में साठ, सत्तर या सौ साल बाद भी उतनी ही साफ, स्पष्ट और ज्यों की त्यों.

इसलिए जब भी आप किसी नाज़ुक लम्हे की मीठी याद कैमरे में क़ैद करना चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म ही इस्तेमाल करें. जिन्हें एक बार खींच कर आप बरसों नाज़ करेंगे.

INDU
ROLL FILM
PANCHRO
125ASA/22DIN

वक़्त, यादों को भले ही धुंधला दे....
पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें कभी धुंधली नहीं होतीं.

इन्दु
INDU®

इन्दु ब्लैक एंड व्हाइट रोल फ़िल्म
और ब्रोमाइड पेपर.

Sista's-HPF.1046.88 HIN A

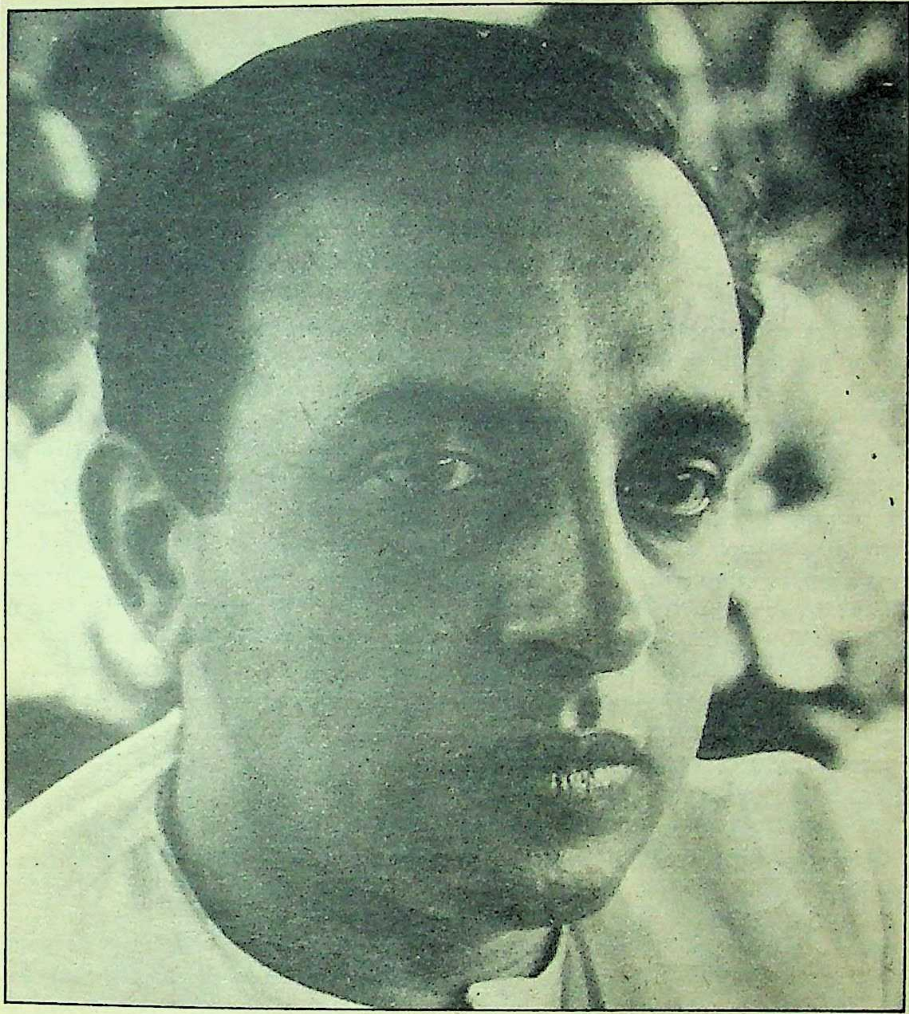

स्वामी को कथित दस्तावेज किसने दिया ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी मानते हैं कि राजनीति में साफ-सुथरी शख्सीयत निहायत बेमानी चीज है, यानी वे स्वयं भी दूध के धोये नहीं हैं। जाहिर है कि वे हर्शमैन का कथित पत्र उछालकर, आड़ में बैठे-बैठे, एक तीर से तीन शिकार करना चाहते हैं। यह चाल उनके लिए आत्मघाती भी हो सकती है। लेकिन इससे, भारतीय लोकतंत्र के लिए त्रासद, यह सत्य तो सामने आ ही जाता है कि विकल्प बनने के लिए अग्रसर विपक्ष में कोई शातिर विभीषण है, जिसने कथित पत्र प्राप्त करने में स्वामी की मदद की और जो अब उनकी पीठ ठोक रहा है। आखिर कौन है वह ?

माइकिल हर्शमैन का वह पत्र, जिसमें उन विपक्षी नेताओं के नाम सूचीबद्ध हैं, जिनके खाते विदेशी बैंकों में हैं, मुझे दिसंबर १९८८ में यूरोप में मौजूद जनता पार्टी के उस वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता से प्राप्त हुआ, जो आजकल जनता दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

—सुब्रह्मण्यम स्वामी

अपने ही साथियों पर आरोप लगाने में माहिर डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी वैसे तो अपनी इस आदत से काफी शोहरत कमा चुके हैं, किंतु ३१ जनवरी को नयी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जनता दल के उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े पर आरोपों की वर्षा करते हुए उन्होंने हर्शमैन के जिस पत्र का जिक्र किया, उसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। जहां तक हेगड़े पर स्वामी द्वारा लगाये गये आरोपों की बात है, तो उससे निबटने के लिए हेगड़े ने खुद कमर कस ली है। हेगड़े ने अपने वकील के जरिए डा० स्वामी को कानूनी नोटिस भेजी है, जिसमें इस बात की मांग की है कि वे (डा० स्वामी) एक हफ्ते के अंदर उनके ऊपर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों का सार्वजनिक रूप से खंडन करें, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दो करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की जायेगी। पत्रकार-वार्ता के दौरान हेगड़े ने यह भी मांग की है कि जिन विपक्षी नेताओं के बारे में स्वामी ने कहा है कि उनके खातों की जांच फेयर फैक्स को सौंपी गयी थी, वे भी स्वामी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

सवाल यह नहीं है कि डा० स्वामी ने जो आरोप लगाये हैं वे आधारहीन हैं या नहीं, मुद्दा तो यह है कि डा० स्वामी को हर्शमैन का पत्र मिला किस नेता से? वह कौन वरिष्ठ नेता है जो विपक्षी नेताओं की छवि चौपट करने के लिए स्वामी को हथियार मुहैया कर रहा है?

स्वामी ने उस वरिष्ठ नेता का नाम नहीं खोला है। स्वामी से पत्रकारों ने काफी घुमा-फिरा कर पूछा, किंतु डा० स्वामी ने यह कहते हुए बात टाल दी थी कि उक्त नेता फिलहाल अपने आपको किसी वाद-विवाद में नहीं फंसाना चाहते, इसलिए वे उनका नाम नहीं बतायेंगे। पत्रकारों के बेहद इसरार पर डा० स्वामी ने इतना वायदा जरूर किया कि सही वक्त पर यदि जरूरत पड़ी, तो वे उक्त नेता का नाम प्रकाश में ले आयेंगे। नतीजतन राजनीतिक हल्कों में उक्त रहस्य की गुत्थी सुलझाने के उद्देश्य से तरह-तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं। इस संबंध में डा० स्वामी से प्राप्त जानकारी के आधार पर 'माया' ने भी कुछ तथ्य जुटाने की कोशिश की, ताकि उक्त नेता को जाना जा सके, जिसका नाम फिलहाल डा० स्वामी बताने से परहेज कर रहे हैं। डा० स्वामी के बयान से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं, वे निम्नलिखित हैं:

० जिस नेता से डा० स्वामी को पत्र मिला, वह जनता दल का नेता होने से पूर्व जनता पार्टी का वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता था।

० डा० स्वामी को पत्र देनेवाला नेता जनता

पार्टी के उन असंतुष्ट नेताओं में से नहीं, जिन्होंने जनता दल में शामिल होने से इनकार किया, क्योंकि स्वामी के बयान से स्पष्ट है कि उक्त नेता जनता दल में महत्वपूर्ण पद पर है।

० डा० स्वामी को पत्र देनेवाला नेता दिसंबर १९८८ में यूरोप में था।

० तथा उसके यूरोप में अच्छे संपर्क हैं।

उल्लेखनीय है कि ३१ जनवरी को धमाका करने से पूर्व डा० स्वामी ने यह भी बयान दिया था कि उनकी खोज में हथियारों के नामी-गिरामी सौदागर अदनान खशोगी ने भी मदद की थी। अदनान खशोगी का नाम प्रकाश में आते ही चंद्रा स्वामी का नाम इस खोज से खुद-ब-खुद जुड़ जाता है, क्योंकि चंद्रा स्वामी खशोगी के अभिन्न मित्रों में से हैं। यदि स्वामी के इस बयान को भी मद्देनजर रखा जाये, तो गुत्थी और उलझ जाती है। फिर भी उपर्युक्त महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर किसी नतीजे तक पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है।

इस संबंध में 'माया' ने अपनी खोजबीन के दौरान जो जानकारी हासिल की, उसके अनुसार दिसंबर १९८८ में ब्रिटेन अथवा यूरोप जानेवाले विपक्षी नेताओं में रामकृष्ण हेगड़े, डीएच देवगौड़ा, इंदुभाई पटेल और चंद्र शेखर के नाम मिले हैं। इस जानकारी की प्राप्ति से इतना तो साफ हो जाता है कि इन्हीं नेताओं में से किसी ने डा० स्वामी को हर्शमैन का पत्र दिया होगा तथा उसी नेता के इशारे पर डा० स्वामी विपक्षी नेताओं की छवि धूमिल करने में जुटे हुए हैं। साथ ही, इस बात के संकेत भी मिलते हैं कि जिस नेता ने डा० स्वामी को दस्तावेज दिये हैं, वह काफी अनुभवी रणनीतिज्ञ है जो चुनाव करीब आते-आते विपक्ष और कांग्रेस-इ दोनों को ब्लैकमेल कर सकता है।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर उपर्युक्त जनता पार्टी के विपक्षी नेताओं में से कौन ऐसा नेता है, जिसकी पहुंच हर्शमैन की एजेंसी तक है। जाहिर है, उक्त नेता की पहुंच इस कंपनी से सीधी होगी और यूरोप में उसका कोई ऐसा दोस्त भी होगा, जिसने दस्तावेज हासिल करने के लिए उक्त नेता की विदेशी मुद्रा की जरूरत पूरी की होगी। अब यहां पर

साक्षात्कार/सुब्रह्मण्यम स्वामी

मैं किस-किस घोटाले पर नजर रखूं

माया : १९७९ में आपने कहा था कि अगले दस सालों में आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या यह माना जा सकता है कि आजकल रहस्योद्घाटन की जो मुहिम आपने चलायी है, वह उसी लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम है?

स्वामी : *मैं जीवनभर भ्रष्टाचार से लड़ता रहा। जब मैं आईआईटी (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी) में प्रोफेसर था, तो अपने साथी प्रोफेसरों के भ्रष्टाचार को उजागर करता था। मुझे तो शुरू से ही भ्रष्टाचार-विरोधी के नाम से जाना जाता है।*

माया : आप कांग्रेसियों के अवैध विदेशी खातों का राजफाश करने की मुहिम क्यों नहीं चलाते? ज्योति बसु भी तो ऐसा ही चाहते हैं?

स्वामी : *मेरी समझ में नहीं आता कि ज्योति बसु और एनटी रामाराव मुझसे ही यह काम क्यों करवाना चाहते हैं? न जाने बसु को यह कहकर क्या मिला कि मैं इस काम में अपने सीआईए से संबद्ध दोस्तों की सहायता लूं। यह काम तो वे भी बखूबी कर सकते हैं। वे केजीबी से संबद्ध अपने मित्रों की सहायता लेकर राजफाश क्यों नहीं करते? ज्योति बसु को अपनी कनाडा यात्रा नहीं भूलनी चाहिए। जो लोग उनके साथ यात्रा पर गये थे, वे कम महत्वपूर्ण नहीं है।*

माया : आप सदा सैद्धांतिक बातें करते हैं। आपने भ्रष्टाचार विरोधी अपनी मुहिम में बोफोर्स घोटाले को शामिल क्यों नहीं किया? संभव था, कुछ नयी बातें सामने आतीं?

स्वामी : *मैं किस-किस घोटाले पर नजर रखूं? फिर बोफोर्स घोटाले पर तो अरुण नेहरू ने ही काम कर दिया था। यही नहीं, वीपी सिंह का भी एक सूत्री कार्यक्रम बोफोर्स घोटाले को प्रकाश में लाना है। इस संबंध में वे क्यों खामोश हैं?*

माया : बोफोर्स घोटाले के मामले में अरुण नेहरू और वीपी सिंह द्वारा अपनायी गयी चुप्पी के पीछे क्या राज है?

स्वामी : *मुझे मालूम नहीं। हां, इतना जरूर है कि दोनों ही कांग्रेसी हैं। एक बार तो वीपी सिंह ने यहां तक कहा था कि राजीव गांधी भगवान कृष्ण हैं और वे (वीपी सिंह) उनके अर्जुन। हो सकता है, राजीव गांधी के हाथ से सत्ता छिन जाने पर यह दोनों पुनः कांग्रेस में शामिल हो जायें।*

माया : अदनान खशोगी जैसे लोगों के संपर्क में रहना क्या आप उचित समझते हैं?

स्वामी : *भाई देखो। वैसे तो मैं बहुतेरे खिलाड़ियों के संपर्क में हूं, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि ऐसा मैं धन बटोरने के लिए करता हूं। जहां तक खशोगी की बात है, वे तो महज हथियारों के व्यापारी हैं। कुछ लोग उनकी दौलत से जलते हैं। जहां तक मुझे पता है, खशोगी ने कोई जुर्म नहीं किया है, वे मुजरिम नहीं हैं। मेरा उनसे संपर्क जरूर है, लेकिन मुझसे उन्हें कोई फायदा नहीं।*

माया : क्या खशोगी की पत्नी इटली की हैं?

स्वामी : *हां।*

—सु०भा०/प०शा०

साक्षात्कार/चंद्र शेखर

मुझे सब कुछ मालूम है

माया : जनता दल के नेता कह रहे हैं कि आप इंदुभाई पटेल और सुब्रह्मण्यम को प्रोत्साहन दे रहे हैं?

चंद्र शेखर : *फिर तो, जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें यह भी चाहिए कि इन्हें (पटेल और स्वामी को) हतोत्साहित करें और रोकें। ऐसे लोग खुलेआम क्यों नहीं कहते कि स्वामी और पटेल झूठ बोल रहे हैं? अगर मुझसे इन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अन्य लोग इन्हें हतोत्साहित करें, वे इसमें मुझे क्यों शामिल करते हैं?...एक बात गांठ बांध लीलिए, हम प्रोक्सी से (अपनी बात दूसरे से कहवा कर) कभी विरोध नहीं करते। मैं मुंह पर विरोध करता हूं। वास्तव में मैं इनसे एक दूसरे से न लड़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि इससे विपक्ष की एकता को धक्का लगेगा। अगर सुब्रह्मण्यम स्वामी और इंदुभाई पटेल मेरी सुनते, तो क्या वे जनता दल में नहीं होते? कैसी मुश्किल में हूं मैं? क्या भगवान के दरबार में मेरी परीक्षा ली जा रही है?*

माया : नहीं-नहीं...

चंद्र शेखर : *तो फिर राजनीति में किसी का बचाव करने के कर्तव्य से मैं कैसे बंधा हूं? नैतिक रूप से अथवा व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी का आभारी क्यों हूं?*

माया : परंतु क्या सुब्रह्मण्यम स्वामी एंड कंपनी आपको इस रूप में पेश करने की कोशिश नहीं कर रही है?

चंद्र शेखर : *करने दीजिए। हर किसी ने मुझे भुनाने की कोशिश की है। किंतु क्या कोई सफल भी हुआ?*

माया : पर उन्होंने खासतौर पर यह चर्चा की है कि उन्हें एक पत्र मिला है?

चंद्र शेखर : *यदि उन्होंने यह चर्चा की है कि मुझे हर्शमैन का पत्र मिला था, तब उन्हीं से पूछिए। मैंने उस पत्र का जिक्र नहीं किया है। मैं उस पत्र के बारे में आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं।*

माया : क्या उस सूची में चौटाला के शामिल होने का कोई अर्थ है, क्योंकि उस मकसद के लिए फेयरफैक्स की कथित सहायता ली जाने के समय देवीलाल सरकार सत्ता में नहीं थी?

चंद्र शेखर : *इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन धारिया मंत्री पद पर नहीं थे, शरद पवार सत्ता में नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर सत्ता में नहीं थे, पर उनके नाम सूची में हैं।*

माया : अच्छा, अगर वीपी सिंह ने फेयरफैक्स की मदद ली हो तो?

चंद्र शेखर : *मुझे नहीं मालूम। यह वीपी सिंह से पूछिए। मैं परिकल्पनात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं*

देता। अगर उन्होंने फेयरफैक्स की मदद ली, तो उन्हीं से पूछिए। मैं वीपी सिंह की तरफ से जवाब कैसे दे सकता हूं?

माया: *किंतु ऐसा हुआ होता, तो क्या राजीव गांधी वीपी सिंह के हटने और नये वित्तमंत्री का पद संभालने के बाद चुप बैठ जाते?*

चंद्र शेखर: *इस विषय में मैं कुछ भी कहनेवाला नहीं हूं। मुझसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि मैं राजीव गांधी और वीपी सिंह की हरकतों पर टिप्पणी करू, क्योंकि यह मेरा विषय नहीं है। वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री बनकर इन लोगों ने जो भी किया, गलत किया। इन्होंने जो किया उसमें सही कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि यह सरकार कोई भला काम करने में सक्षम नहीं है। किसने किसकी मदद ली, मुझे नहीं मालूम।*

माया: *पर उनका कहना है कि आप हर्शमैन से मिले हैं?*

चंद्र शेखर: *उन्हें कहने दीजिए कि मैं हर्शमैन से मिला हूं। वे यह भी कहते हैं कि मैं देवीलाल से मिला हूं, इससे क्या? मैं तो ढेर सारे लोगों से मिलता हूं। क्या मैं अखबार में छपवाया करू कि किस-किससे मिला?*

माया: *पर क्या आप उनसे (हर्शमैन से) मिले हैं?*

चंद्र शेखर: *मैं नहीं बताऊंगा कि मैं उनसे मिला या नहीं, क्योंकि आपको यह बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किससे मिला। और यह नहीं बताया जाता—न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर, बल्कि निजी जीवन में भी। मेरा खयाल है, आप भी नहीं बतायेंगे कि आप किस किससे मिलते हैं।*

माया: *हां, पर मैं राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूं।*

चंद्र शेखर: *मैं भी राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूं। मैं अंशकालिक राजनीतिक हूं। मेरे जीवन का दस प्रतिशत भाग ही राजनीतिक है, नब्बे प्रतिशत व्यक्तिगत जीवन जैसा—आप जैसा—ही है।*

माया: *सुब्रह्मण्यम स्वामी, जिन्हें आप अपना दोस्त मानते हैं, का आरोप है कि आप विपक्षी नेताओं के विदेशी बैंकों में जमा अवैध धन के बारे में जानते हैं?*

चंद्र शेखर: *बिलकुल सही है। मुझे सब कुछ मालूम है। यदि मैं यह कहूं कि मुझे उस बारे में स्वामी से ज्यादा जानकारी है, तो गलत न होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसकी चर्चा करता फिरूं। फिर लोग तो मेरे बारे में खूब जानते हैं कि मैं जानता तो सब कुछ हूं, लेकिन कहता कुछ नहीं। यों समझ लें कि मैं ऐसी जानकारियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करता। हां, यदि मुझे इस बात का अहसास हो जाये कि मेरी जानकारी देश को संकट से छुटकारा दिला सकती है, तो मैं उसे बताते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं।*

माया: *क्या देश का भविष्य खतरे में हैं?*

चंद्र शेखर: *नहीं, नहीं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास बदलना हर मामूली आदमी के बस का काम नहीं।*

—सु॰भा॰/प॰शा॰

यदि यह साबित हो जाये कि जनता पार्टी के किस नेता का कौन दोस्त है, जिसने अदनान खशोगी से इस सिलसिले में मुद्रा हासिल की, तो गुत्थी किसी हद तक सुलझ सकती है। जहां तक अदनान खशोगी की बात है, तो उनके बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्हें धन और संपर्क की कमी नहीं। अब दो ही रास्ते हैं। एक तो यह कि उक्त नेता का अदनान से सीधा संपर्क हो अथवा कोई दोस्त माध्यम हो। सवाल यह उठता है कि अदनान खशोगी क्यों किसी की मदद करेंगे? उनको इस मदद से क्या लाभ पहुंचा होगा? इसका सीधा जवाब चंद्रा स्वामी हैं, क्योंकि जहां चंद्रा स्वामी भारतीय नेताओं के दोस्त और विश्वासपात्र हैं, वहीं उनका संपर्क अदनान से भी बहुत अच्छा है। चंद्रा स्वामी के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि वे हर दिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद अपने राजनीतिक दोस्त और दुश्मनों की सूची में फेरबदल करते रहते हैं। इसलिए यह गुंजाइश निकलती है कि ऐसा सोचा जाये कि हो सकता है, जिस जनता दल के नेता का नाम डा॰ स्वामी छिपा रहे हैं, उसने चंद्रा स्वामी से काम कराने का आग्रह किया हो, जिसके चलते अदनान ने मदद की हो।

अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि हेगड़े, पटेल, देवगौड़ा और चंद्र शेखर में से किसके-किसके चंद्रा स्वामी से अच्छे संबंध हैं। जांच-पड़ताल के बाद पता लगता है कि हेगड़े और चंद्र शेखर के सिवा चंद्रा स्वामी की किसी से पटरी नहीं खाती। मजे की बात यह है कि हेगड़े और चंद्र शेखर दोनों ही पहले जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता थे और अब जनता दल में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। तो क्या यह मान लिया जाये कि हेगड़े ने डा॰ स्वामी को दस्तावेज दिये और यदि नहीं तो फिर क्या चंद्र शेखर ने स्वामी की मदद की?

अब यहां पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि डा॰ स्वामी की इन दोनों नेताओं में से किससे ज्यादा पटती है और वे कब से किसके संपर्क में हैं। पता चलता है कि स्वामी पिछले छह महीनों से चंद्र शेखर के बहुत करीब हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करके चंद्र शेखर ने अजीत सिंह को चढाने और हेगड़े एंड कंपनी को गिराने का राजनीतिक खेल खेला है। जहां तक देवगौड़ा और इंदुभाई पटेल की बात है, तो

साक्षात्कार/रामकृष्ण हेगड़े

पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान न मिलने से वे असंतुष्ट हैं

माया: ***आखिर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आपको निशाना क्यों बनाया हुआ है?***

हेगड़े: *उनकी तो आदत है कि वे अपनों पर ही हमला करते हैं। जब वे जनसंघ में थे, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को निशाना बनाया था। बाद में जनता पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने चंद्र शेखर को आड़े हाथों लिया।*

माया: *आपका क्या खयाल है, वे ऐसा क्यों करते हैं?*

हेगड़े: *पहले मुझे ऐसा लगता था कि चूंकि स्वामी काफी महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए शायद उन्हें देश के बड़े नेता दुश्मन नजर आते हैं। उनका रास्ता साफ रहे इसीलिए वे ऐसा करते होंगे। जहां तक मेरी बात है, तो असलियत यह है कि चूंकि हम दोनों ही दक्षिण के हैं और एक जाति के हैं, इसलिए स्वामी मुझे अपने राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा अवरोध समझते हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के सिवा कोई क्या कर सकता है?*

माया: *कुछ विपक्षी नेता स्वामी को कांग्रेस-इ का एजेंट मानते हैं तथा पेशेवर ब्लैकमेलर की संज्ञा देते हैं। आपका उनके बारे में क्या खयाल है?*

हेगड़े: *इसमें संदेह नहीं कि वे कांग्रेस-इ की सहायता कर रहे हैं और कांग्रेस-इ की मदद से ही विपक्षी नेताओं पर हमला कर रहे हैं। जगजाहिर है कि ऐसी हरकतें कांग्रेस के दलाल के सिवा कौन कर सकता है।*

माया: *क्या आपने स्वामी से मनमुटाव का कारण कभी जानने की कोशिश की?*

हेगड़े: *हां, कुछ समय पहले बीजू पटनायक ने स्वामी से मिलने के लिए मुझसे आग्रह किया था। जिसके लिए मैं तैयार हो गया था।*

माया: *तो क्या आपकी स्वामी से मुलाकात हुई?*

हेगड़े: *हां, वे मुझसे मिलने के लिए मोदी स्टेट आये थे। उन्होंने आते ही कहा कि चूंकि मैं उनसे मिलना चाहता था, इसलिए वे आये हैं। इस पर मैंने जवाब दिया था कि मुझे तो ऐसा पता है कि वे खुद मुझसे मिलना चाहते थे। इस पर फिर उन्होंने पहले की तरह जवाब दिया। खैर, उस मुलाकात के दौरान मैंने कहा था कि इस तरह के गलत आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन वे माने नहीं। लगता है, पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान न मिलने के कारण वे असंतुष्ट हैं।*

माया: *स्वामी ने आप पर जो आरोप लगाये हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?*

हेगड़े: *प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं उठता। अभी तक टेलीफोन-टेपिंग कांड में भी यह साबित नहीं किया जा सका कि आदेश मैंने दिये थे।*

माया: *क्या आपको यह महसूस होता है कि आपके ही कुछ साथी स्वामी की मदद कर रहे हैं?*

हेगड़े: *यह मैं कैसे कह सकता हूं? मुझे तो अपने साथियों पर विश्वास है।*

—सु॰भा॰/प॰शा॰

दिन भर आपको खुशबू दे

बस, जेट फ्रेग्रेंस मेट लीजिए और बाई ओर की हीटिंग प्लेटपर रख दीजिए. स्विच ऑन कीजिए... वाह.... सारा दिन खुशबू से महकाता रहे पूरे दस घंटों तक. कितना सुखद है जेट-एज अगरबत्ती की सुगंध के बीच काम करना!

रात भर मच्छरों को भगाए

बस, मैट को दाई ओर की हीटिंग प्लेट पर रख दीजिए. बटन ऑन कीजिए.... बस, मच्छरों को अलविदा.. फुर्ररर.... पूरे दस घंटों तक चैन की नींद सोइए. कितना सुखद है मीठे सपनों में डूबे रहना!

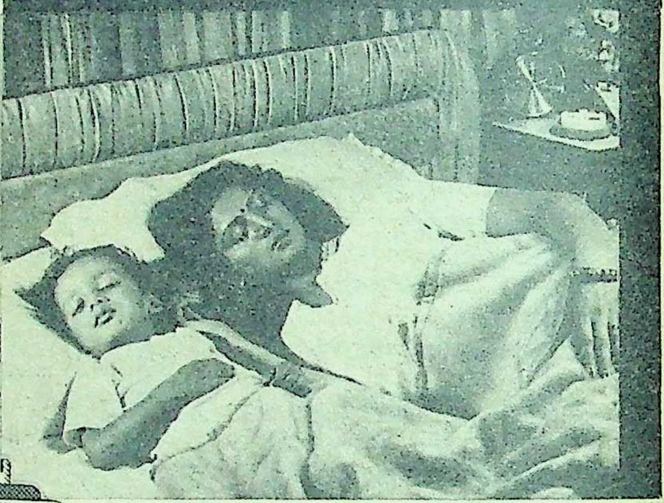

इन स्थानों के लिए उत्तम:

घर, दफ्तर,
ब्यूटी पार्लर,
रेस्तरां, अस्पताल
मंदिर

- मस्किटो मैट्स कैमिकल्स मै दुनिया-भर में जानी-मानी सुमिटोमो जापान की आधुनिक टेक्नालॉजी द्वारा निर्मित.
- एल्यूमीनियम में पैक एकमात्र मैट जो ज़्यादा देर तक असर दिखाए, मच्छरों से पूरी सुरक्षा दिलाए.
- इसकी असरकारक शक्ति १०० % सुरक्षित रहे यानी आपके पैसों का १०० % मूल्य चुकाए.

Jet FRAGRANCE MAT
Jet MOSQUITO MAT
DOUBLE ACTION
FRAGRANCE MAT
MOSQUITO MAT
भारतमें पहलीबार
Jet vaporiser

BIDHAN-SE-1/88 HIN

जेट डबल एक्शन वेपोराइज़र

जनस्वास्थ्य और आरोग्य के लिए समर्पित नाम.

सोनिक इलेक्ट्रोकैम प्रा. लि.
३८, पटेल नगर, इंदौर-४५२ ००१. फोन: ६०५०७.

उन पर संदेह करना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ने जनता दल में शामिल होना स्वीकार नहीं किया है, जबकि डा० स्वामी का कहना है कि जिस नेता से उन्हें दस्तावेज प्राप्त हुए वे जनता दल में वरिष्ठ पद पर हैं। देवगौड़ा और पटेल पर से नजरें हटते ही, मात्र दो नेता, हेगड़े और चंद्र शेखर ही ऐसे बचते हैं जो डा० स्वामी द्वारा दिये गये बयान के अनुसार 'फिट' बैठते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्र शेखर का दायें हाथ माने जानेवाले विश्वासपात्र गौतम का कहना है कि दिसंबर '८८ में चंद्र शेखर यूरोप में थे। गौतम के अनुसार दिसंबर '८८ में अपने मित्र भगवान अवधूत राम के आमंत्रण पर चंद्र शेखर ने फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड का दस दिवसीय दौरा किया था। जब 'माया' ने गौतम से दस्तावेज हासिल किये जाने के मुद्दे पर जानकारी चाही, तो गौतम केवल इतना कहकर चुप रह गये कि ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर उनका कुछ बोलना बेहतर नहीं।

गुत्थी को इस हद तक सुलझा लेने पर इतना तो तय हो जाता है कि इन्हीं दोनों (हेगड़े व चंद्र शेखर) नेताओं में से किसी से डा० स्वामी को दस्तावेज मिले होंगे। यदि यह अनुमान गलत साबित होता है, तब ही तीसरे किसी व्यक्ति की संभावना बनती है तथा उस तीसरे व्यक्ति के बारे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सचमुच वह व्यक्ति चंद्र शेखर की छवि धूमिल करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। खैर, तीसरे व्यक्ति की संभावना को यदि फिलहाल दबाकर रखा जाये, तो यह बात उजागर होती है कि ३१ जनवरी की डा० स्वामी की प्रेस कांफ्रेंस के फौरन बाद चंद्र शेखर के यूरोप के दौरे की बात जंगल में आग की तरह फैलने लगी थी और कुछ घंटों के अंदर ही विपक्षी राजनीतिक हल्कों में चंद्र शेखर पर संदेह किया जाने लगा था। हो सकता है चंद्र शेखर के दिसंबर '८८ के दौरे से इस दस्तावेज तथा डा० स्वामी के बयान का कोई वास्ता न हो, किंतु बयान के फौरन बाद से जिस तरह चंद्र शेखर पर संदेह किया जाने लगा तथा उनका नाम उछाला गया, उससे साफ जाहिर होता है कि यदि कोई तीसरा व्यक्ति इस दस्तावेज से जुड़ा है, तो सचमुच वह जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चंद्र शेखर की छवि धूल धूसरित करना चाहता है। डा० स्वामी द्वारा दस्तावेज का धमाका किये जाने के बाद तरह-तरह की बातें सामने आयीं। किसी ने कहा कि चंद्र शेखर दिसंबर '८८ में इंदुभाई पटेल, जयंत मल्होत्रा, वाराणसी के अपने एक मित्र और गुजरात के व्यापारी छोटूभाई के साथ यूरोप के दौरे पर गये थे। उल्लेखनीय है कि छोटूभाई के जर्मनी में बड़े अच्छे संपर्क हैं। कहनेवालों ने यहां तक कहा कि चंद्र शेखर का यह दल दौरे के दौरान रोम, पेरिस और स्पेन भी गया, जहां वे खशोगी के अतिथिगृह में चंद्रा स्वामी के अतिथि के रूप में ठहरे भी। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बयान हाल में इंदुभाई पटेल ने दिया कि उन्होंने और चंद्र शेखर ने यूरोप में रहनेवाले अपने एक मित्र के घर हर्शमैन से मुलाकात की। पटेल के इस बयान से यह बात साफ हो गयी कि दिसंबर '८८ में चंद्र शेखर ने हर्शमैन से मुलाकात की। जहां तक यूरोप के मित्र की बात है, यदि उपर्युक्त आकलन सही है तो मित्र अदनान खशोगी और चंद्रा स्वामी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? हालांकि चंद्र शेखर से जब पटेल के बयान के आधार पर बातचीत हुई, तो उन्होंने हर्शमैन से अपनी मुलाकात की बात को गोलमोल रखना चाहा। किंतु उन्होंने इतना जरूर कहा कि वे डा० स्वामी से ज्यादा इस बारे में जानकारी रखते हैं (देखें साक्षात्कार)। हर्शमैन भी न तो इस बात से इनकार करते हैं कि दिसंबर '८८ में उनकी मुलाकात चंद्र शेखर से हुई, न ही स्वीकार करते हैं कि वे चंद्र शेखर से मिले थे। हाल में दिये गये एक बयान में हर्शमैन ने बड़ी गोलमोल बात कही। उन्होंने कहा, "सही बात तो यह है कि पिछले कुछ सालों में मैं इतने भारतीय नेताओं से विभिन्न स्थानों पर मिला हूं कि मुझे कुछ याद नहीं।"

उपर्युक्त बयानों को यदि मद्देनजर रखा जाये, तो चंद्र शेखर संदेह के घेरे में आते हैं, क्योंकि इंदुभाई पटेल का जनता दल की राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं। किंतु यहां पर इस बात का उल्लेख करना भी उचित होगा कि चंद्र शेखर के ही एक मित्र, जो फिलहाल जनता दल में हैं, का कहना है, "वैसे चंद्र शेखर इस तरह से लुक-छिपकर राजनीति नहीं करते। वे ही एक ऐसे नेता हैं जो खुलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं।" चंद्र शेखर के मित्र की यह बात किसी हद तक सही भी है।

जहां तक दूसरे जनता दल के वरिष्ठ नेताओं की बात है, वे इस बात से सहमत हैं कि डा० स्वामी का नया धमाका जनता दल की राजनीति में दरार डालने के लिए किया गया है, ताकि चंद्र शेखर की छवि संदेहास्पद हो जाये और वे जनता दल छोड़ने पर मजबूर हो जायें। इस संबंध में जनता दल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, "सचाई तो यह है कि डा० स्वामी ने दस्तावेज अपने कांग्रेसी दोस्तों की मदद से हासिल किये हैं।"

बहरहाल, सचाई जो कुछ भी हो, डा० स्वामी जो खेल खेल रहे हैं उससे उनको कोई नुकसान होता नजर नहीं आता। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय राजनीति में 'मिस्टर क्लीन' होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। इस दस्तावेज को लेकर जिस तरह की गंदी राजनीति हो रही है, लगता है उसके चलते इस दस्तावेज का भी वही हश्र होगा जो इससे पहले के हर्शमैन के दो दस्तावेजों का हुआ था, जिसके चलते इंडियन एक्सप्रेस समूह पर छापा डाला गया था। छापे के बाद कुछ दिनों तक वाद-विवाद और संदेह की स्थिति बनी रही और धीरे-धीरे मामला शांत हो गया। किंतु एक वरिष्ठ अधिकारी और एक नामी-गिरामी समाचार-समूह का नाम दागदार हुआ। यदि यह दस्तावेज भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता रहा, तो उसका भी वही अंजाम होगा और सचाई एक बार फिर छिपी रह जायेगी।

—सुधा भाटिया

> जहां तक दूसरे जनता दल के वरिष्ठ नेताओं की बात है, वे इस बात से सहमत हैं कि डा० स्वामी का नया धमाका जनता दल की राजनीति में दरार डालने के लिए किया गया है, ताकि चंद्रशेखर की छवि संदेहास्पद हो जाये और वे जनता दल छोड़ने पर मजबूर हो जायें।

◆◆

वीपी सिंह कहते हैं

◆ वित्तमंत्री की हैसियत से अपने कार्यकाल में अपने हस्ताक्षर से मैंने सिर्फ एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी के सौदे की जांच के आदेश जारी किये थे। सभी जानते हैं कि इस जांच के आदेश के नतीजे क्या निकले?

◆ लोग समझते हैं कि सामंती व्यवस्था की तरह मंत्री भी किसी मामले की जांच या किसी तरह के छापे का स्वतंत्र अधिकार रखता है। किंतु यह गलत है। यदि अकेला मंत्री ही अपनी मर्जी से इस तरह के आदेश जारी करे, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

◆ यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में अधिकारी नियमों और संविधान को मद्देनजर रखते हुए ही कार्य करते हैं। चाहे वह फेरा से संबंधित मामला हो, या आयकर से संबंधित, मंत्री की मर्जी पर कानून नहीं बदल सकते।

◆ मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अपने कार्यकाल में मैंने सिर्फ पनडुब्बी सौदे की जांच के आदेश जारी किये थे जिसको आज भी सुब्रह्मण्यम स्वामी नजरअंदाज किये बैठे हैं। असलियत यह है कि स्वामी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्तों पर लगे आरोपों की किसी-न-किसी रूप में लीपापोती करना चाहते हैं।

◆ मुझे जहां तक मालूम है किसी राजनीतिक के खिलाफ जांच का कोई आदेश नहीं था।

◆ यदि ऐसी कोई सूची थी, जिसको मैंने अपने कार्यकाल में दबाये रखा, तो मेरे बाद एक वर्ष तक वित्तमंत्री का भी पद संभालने वाले प्रधानमंत्री ने उसका रहस्योद्घाटन क्यों नहीं किया?

◆ स्वामी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, यदि वे सच हैं, तो उससे राजीव गांधी की ही अक्षमता उजागर होती है, क्योंकि वे किसी तरह का उचित कदम नहीं उठा पा रहे हैं।

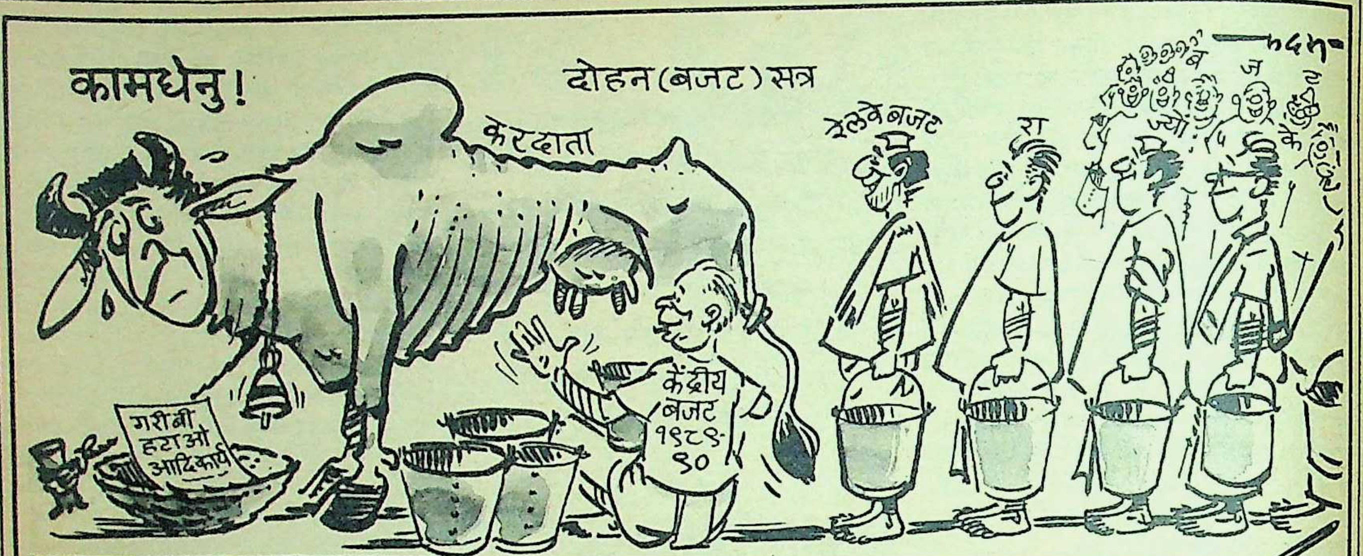
कामधेनु!
दोहन (बजट) सत्र
करदाता
केंद्रीय बजट १९८९-९०
गरीबी हटाओ आदि कार्य
रेलवे बजट
रा
ब
ज्यो
ज
के
ए

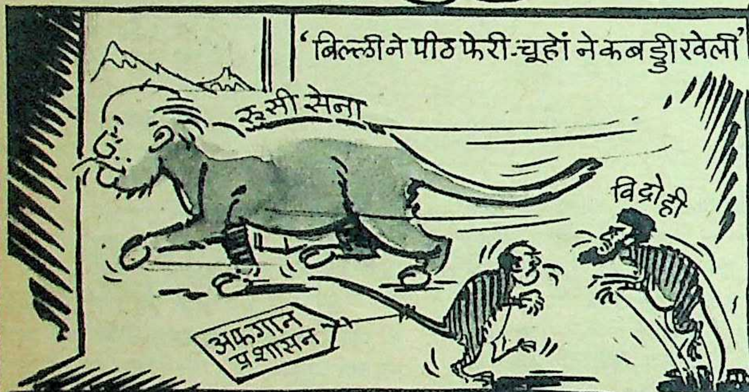
'बिल्ली ने पीठ फेरी-चूहों ने कबड्डी खेली'
रूसी सेना
विद्रोही
अफगान प्रशासन

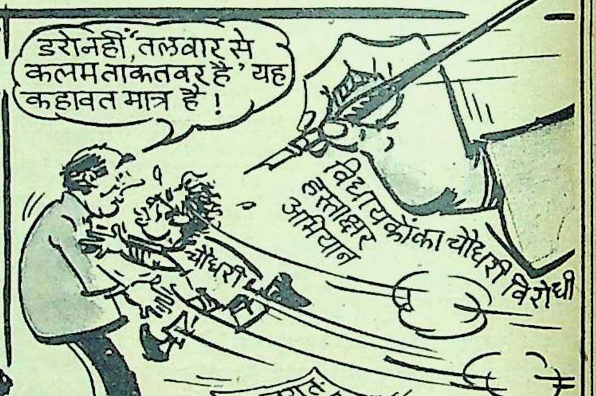
डरो नहीं, 'तलवार से कलम ताकतवर है' यह कहावत मात्र है!
विधायकों का हस्ताक्षर अभियान
चौधरी विरोधी
चौधरी
गुजरात: असंतुष्ट

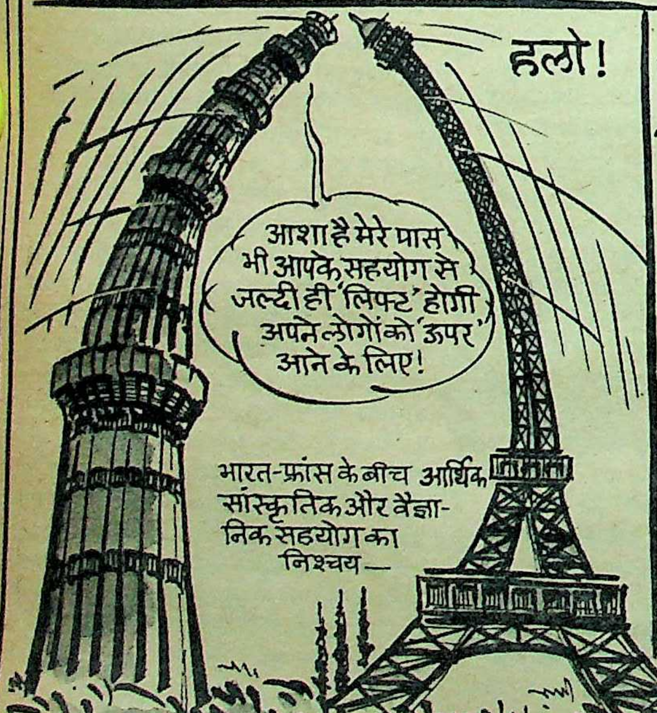
हलो!
आशा है मेरे पास भी आपके सहयोग से जल्दी ही 'लिफ्ट' होगी अपने लोगों को 'ऊपर' आने के लिए!
भारत-फ्रांस के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग का निश्चय—

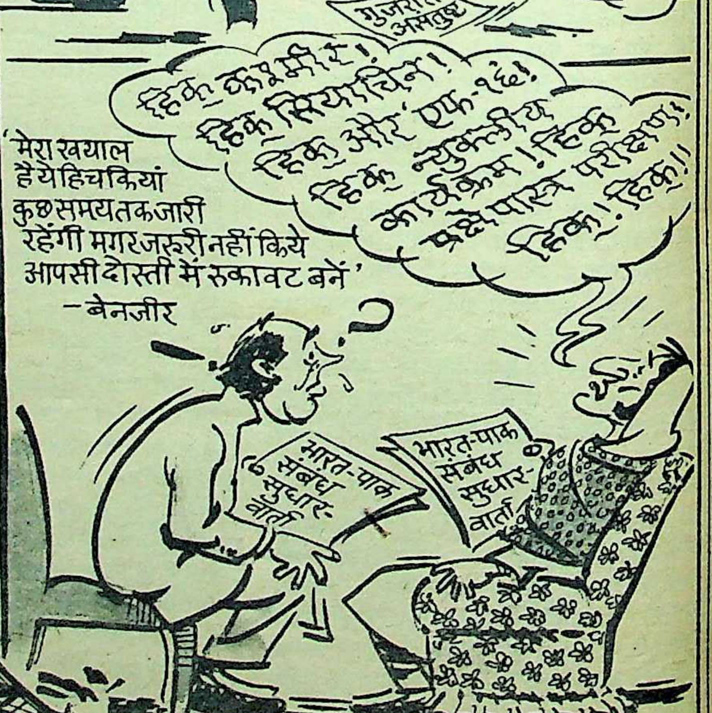
'मेरा खयाल है ये हिचकियां कुछ समय तक जारी रहेंगी मगर जरूरी नहीं कि ये आपसी दोस्ती में रुकावट बनें'
—बेनजीर
हिक् कश्मीर! हिक् सियाचिन! हिक् और 'एफ-१६'! हिक् न्युक्लीय कार्यक्रम! हिक् प्रक्षेपास्त्र परीक्षण! हिक! हिक!!
भारत-पाक संबंध सुधार-वार्ता
भारत-पाक संबंध सुधार-वार्ता

सलाहकार या राजीव गांधी के संकट के सूत्रधार ?

बहुत देर हो गयी : राजीव गांधी

इस समय राजीव गांधी
हर राज्य में अपनी पार्टी में उठे विद्रोह के
भूचाल की जद में हैं।
पार्टी में शांति स्थापित करने के लिए
उन्होंने हर राज्य में
अपने सलाहकारों और विशेष दूतों को लगा
रखा है, लेकिन आग बुझने के बजाय और
भड़कती जा रही है। क्या कारण
है कि जिन लोगों को राजीव गांधी ने
अपना संकटमोचक बना रखा है,
वही लोग
आग में घी डाल रहे हैं ?
विभिन्न राज्यों में राजीव गांधी के दूतों की
भूमिका क्या रही है ? इस समय
राजीव गांधी जिस संकट से जूझ रहे हैं,
क्या विपक्ष उसका फायदा उठाने की
स्थिति में है ?

समस्याओं का अंबार: राजीव गांधी

बुझाते हैं कम, लगाते हैं ज्यादा: गुलाम नबी आजाद

छाया: बसीमुन

> विधायक ने तैश में आकर कहा, "सुनिए, मैं तीन बार विधायक चुना जा चुका हूं और एक बार लोकसभा के चुनाव में हारा जरूर था, लेकिन एक लाख से ज्यादा वोट पा चुका हूं, जबकि आप अपने राज्य (जम्मू-कश्मीर) से चुनाव लड़ने का ख्वाब तक नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति में आप मुझसे बात करना नहीं चाहते, तो पार्टी का भट्ठा तो बैठेगा ही।"

बात पते की है कि किसी व्यक्ति को पहचानना हो, तो उसकी सोहबत को देखिए—यानी उसके संगी-साथी-सलाहकार कौन हैं? व्यक्ति की मुसीबतों और आसानियों के कारण भी इसी सोहबत में छिपे रहते हैं। शायद यही कारण है कि आज राजीव गांधी जिस संकट से दो-चार हैं, उसके लिए उनके सलाहकारों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक युवा इंका विधायक ने एक उदाहरण देकर बताया कि राजीव गांधी ने ऐसे लोगों को पार्टी को संभालने का काम दे रखा है जो जहां शांति है, वहां भी बवाल मचवा सकते हैं। विधायक का कहना था कि लखनऊ में १० फरवरी को आयोजित इंका महाधिवेशन में जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सदस्यों को राजीव गांधी के सामने ही डांटा (देखिए खबरों के आगे, खबरों के पीछे) उससे उत्तर प्रदेश में भी वैसी आग भड़क सकती है, जैसी बिहार, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में भड़की हुई है। इस विधायक का कहना था कि १६ फरवरी को इंका के विधायकों, पदाधिकारियों और जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने जो गुबार निकाला, उसके पीछे भी १० फरवरी को गुलाम नबी आजाद के आहत-अपमानित करने वाले 'हिटलरी रवैये' को देखा जा सकता है। १६ फरवरी को आगामी चुनाव की रणनीति तय करने के लिए लखनऊ में बैठक बुलायी गयी थी, लेकिन मुख्य मुद्दे पर किसी ने कोई बात नहीं सुनी, बल्कि पार्टी एवं सरकार की बागी स्वर में भर्त्सना की गयी। किसी ने कहा कि सरकार में कालगर्ल्स भेंट करनेवाले मंत्री हैं, तो किसी ने कहा कि केवल साढ़े पांच मंत्री ही काम के हैं। यह स्थिति इंका शासित उस राज्य की है, जहां नारायण दत्त तिवारी जैसे वरिष्ठ, सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं और पार्टी का मनोबल बनाये रखने में जुटे हैं। "लेकिन कोई दिल्ली से आकर पलीता लगाये और जमालो की तरह दूर खड़ा तमाशा देखे, तो बेचारे तिवारी क्या कर सकते हैं?" एक वरिष्ठ मंत्री ने टिप्पणी की।

मध्य प्रदेश में: गुलाम नबी आजाद ने मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के उत्तराधिकारी के चुनाव में जो भूमिका निभायी, उसके किस्से भी भोपाल में कारबाइड गैस की तरह फैल रहे हैं। बताया जाता है कि एक विधायक आजाद से कुछ कहना चाहता था, लेकिन आजाद ने बीच में उसकी बात काटते हुए अंग्रेजी में जो कुछ कहा, उसका लब्बो-लुबाब यह था कि मैं आप जैसे लगुओं-भगुओं से बात करना नहीं चाहता। इस पर विधायक ने तैश में आकर कहा, "सुनिए, मैं तीन बार विधायक चुना जा चुका हूं और एक बार लोकसभा के चुनाव में हारा जरूर था, लेकिन एक लाख से ज्यादा वोट पा चुका हूं, जबकि आप अपने राज्य (जम्मू-कश्मीर) से चुनाव लड़ने का ख्वाब तक नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति में आप मुझसे बात करना नहीं चाहते, तो पार्टी का भट्ठा तो बैठेगा ही।" हो सकता है इस किस्से को कुछ नमक-मिर्च लगाकर सुनाया जा रहा हो, लेकिन यह बात अब सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में राजीव गांधी के दूतों ने जो भूमिका निभायी, उससे गुत्थी सुलझी कम, उलझी ज्यादा। राजीव गांधी के अन्य संकटमोचक बूटा सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनकी 'हवस' मध्य प्रदेश में सुलह-सफायी के बजाय अर्जुन सिंह को 'जलील' करने की थी। बूटा सिंह भी राजीव गांधी के ऐसे सलाहकार हैं जो पजाब में तो घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान से सांसद बनकर हर राज्य में अपनी चौधराहट जमाते रहते हैं। राजस्थान में हरिदेव जोशी के बागी होने के पीछे बूटा सिंह के रवैये की अहम भूमिका मानी जाती है।

आलाकमान में आलाकमान: 'एक हाईकमान में बहुत सारे हाईकमान हैं,' सलाहकारों के निहित स्वार्थों को देखते हुए बिहार के उत्तेजित असंतुष्ट विधायकों की इस टिप्पणी को निराधार नहीं कहा जा सकता। राजीव गांधी के अधिकांश दूत, सलाहकार और संकटमोचक उनके निर्देशों का पालन करने के बजाय विभिन्न प्रदेशों में अपने निजी युद्धों में भी शिरकत करने लगते हैं। पटना में बूटा सिंह और फोतेदार एकमत नहीं थे। बिहार में असंतुष्टों को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने जगन्नाथ मिश्र, एलपी साही, बिंदेश्वरी दुबे और तारिक अनवर की एक चार सदस्यीय समिति तो

जरूर बना दी, लेकिन ये चारों न केवल मुख्यमंत्री की कुरसी पर नजर टिकाये रहे हैं, बल्कि इनके अपने-अपने निहित स्वार्थ भी हैं। दुबे के हवाले से तो यह खबर भी प्रसारित हो गयी थी कि भागवत झा आजाद का पत्ता साफ होनेवाला है। इसके लिए गणतंत्र दिवस की परेड में दुबे को राजीव गांधी की यह झाड़ भी सुननी पड़ी, "अब आप मुख्यमंत्रियों के बारे में फैसले लेने लगे हैं।" अगले दिन ही दूरदर्शन के प्रातःकालीन प्रसारण में दुबे का चेहरा उनके इस वक्तव्य के साथ दिखाया गया कि उन्होंने भागवत झा आजाद के हटने के संबंध में कभी कुछ नहीं कहा है।

अपनी-अपनी डफली : समस्याएं उग्र रूप कैसे धारण करती हैं, इसका उदाहरण है बिहार, जहां सलाहकारों ने ऐसी रिपोर्टें तैयार की जो एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाती थीं। बूटा सिंह ने राजीव को जो रिपोर्ट दी, फोतेदार की रिपोर्ट उससे भिन्न थी और चार सदस्यीय समिति द्वारा दी गयी तीसरी रिपोर्ट उक्त रिपोर्टों से मेल नहीं खाती थी। इस प्रकार राजीव के सलाहकारों और प्रतिनिधियों के अपने-अपने निहित स्वार्थों और विभिन्न प्रदेशों में उनके द्वारा बनाये गये लघु साम्राज्यों का असर यह हो रहा है कि राजीव गांधी एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं।

> **गुलाम नबी आजाद, शीला कौल, शीला दीक्षित, बूटा सिंह, फोतेदार जैसे राजीव गांधी के प्रायः सभी खास सलाहकारों के विभिन्न प्रदेशों में अपने-अपने चहेते हैं। बताया जाता है कि इन चहेतों के माध्यम से ये लोग अपने विरोधियों को झटका देने के लिए समय-समय पर समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। ये लोग राजीव गांधी को ऐसी रिपोर्टें भी देते रहते हैं, जिनसे उनके चहेतों की छवि तो सुर्ख हो, लेकिन विरोधियों की छवि धूमिल हो।**

पार्टी हित के बजाय स्वार्थ सिद्धि की चिंता : बूटा सिंह

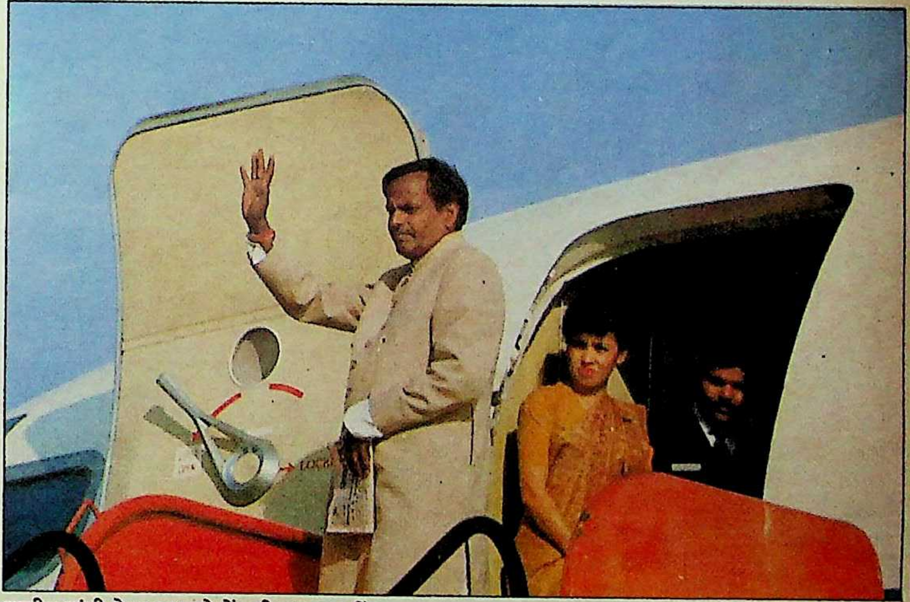
राजीव गांधी के उड़न दस्ते में : वीर बहादुर सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

तमिलनाडु चुनाव के बारे में गुप्तचरों की रिपोर्ट थी कि जयललिता से हाथ मिलाये बिना कांग्रेस-इ का अधिक सीटों पर विजयी होना संदिग्ध है। खुफिया सूत्रों ने पहले दिसंबर और फिर जनवरी के शुरू में इस तथ्य से प्रधानमंत्री को अवगत भी करा दिया था। लेकिन जीके मूपनार और पी चिदंबरम ने अपने-अपने स्वार्थों के कारण जयललिता से उस समय भी चुनावी गठबंधन नहीं होने दिया, जब वे कांग्रेस-इ को ५५ प्रतिशत सीटें देने के लिए राजी हो गयी थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस-इ ने तमिलनाडु के प्रतिष्ठात्मक विधानसभा चुनाव में अपमानजनक हार का सामना ही नहीं किया, बल्कि पूरे देश में उसकी साख मिट्टी में मिल गयी और सभी कांग्रेसियों को पार्टी की लुटिया डूबती नजर आने के कारण नेतृत्व की अवहेलना और मनमानी करने का मौका मिल गया।

व्यक्तिगत प्रतिशोध : गुलाम नबी आजाद, शीला कौल, शीला दीक्षित, बूटा सिंह, फोतेदार जैसे राजीव गांधी के प्रायः सभी खास सलाहकारों के विभिन्न प्रदेशों में अपने-अपने चहेते हैं। बताया जाता है कि इन चहेतों के माध्यम से ये लोग अपने विरोधियों को झटका देने के लिए समय-समय पर समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। ये लोग राजीव गांधी को ऐसी रिपोर्टें भी देते रहते हैं, जिनसे उनके चहेतों की छवि तो सुर्ख हो, लेकिन विरोधियों की छवि धूमिल हो। इसके फलस्वरूप राजीव गांधी को न केवल विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेसी नेताओं में व्याप्त गुटबाजी को सहन करना पड़ रहा है, बल्कि वे अपने सलाहकारों के बीच व्याप्त मतभेदों को भी सहन करने के लिए मजबूर हैं।

अब कांग्रेस-इ में रफी अहमद किदवई जैसा कोई आदमी नहीं है। किदवई ने जवाहरलाल नेहरू के लिए परेशानी का कारण बन चुके शेख अब्दुल्ला को श्रीनगर जाकर गिरफ्तार करने का जटिल और खतरनाक फैसला लिया था। किदवई और लालबहादुर शास्त्री लखनऊ में डा॰ संपूर्णानंद जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को शांत करने में भी कामयाब हो गये थे। उस समय डा॰ संपूर्णानंद के साथ बहुसंख्यक विधायक था और वे मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ने के लिए आमादा थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पसंद नहीं था। किदवई और शास्त्री दोनों उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वे पंडित नेहरू के इच्छानुसार, डा॰ संपूर्णानंद को समझाने में इस कारण सफल हो सके थे, क्योंकि प्रदेश में उनके निहित स्वार्थ नहीं थे और न ही उनके ऐसे गुट ही थे, जैसेकि राजीव गांधी के आदमियों के इस वक्त हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती दिनों में हालात ऐसे नहीं थे। तब विभिन्न प्रदेशों में व्याप्त गुटबाजी काफी हद तक काबू में थी।

तब महाराष्ट्र के मामलों के प्रभारी वीपी सिंह, वसंत दादा पाटील और भोंसले के बीच छिड़ी जंग को शांत करने में इसी वजह से कामयाब हो गये थे, क्योंकि वे खुद तहेदिल से आलाकमान की

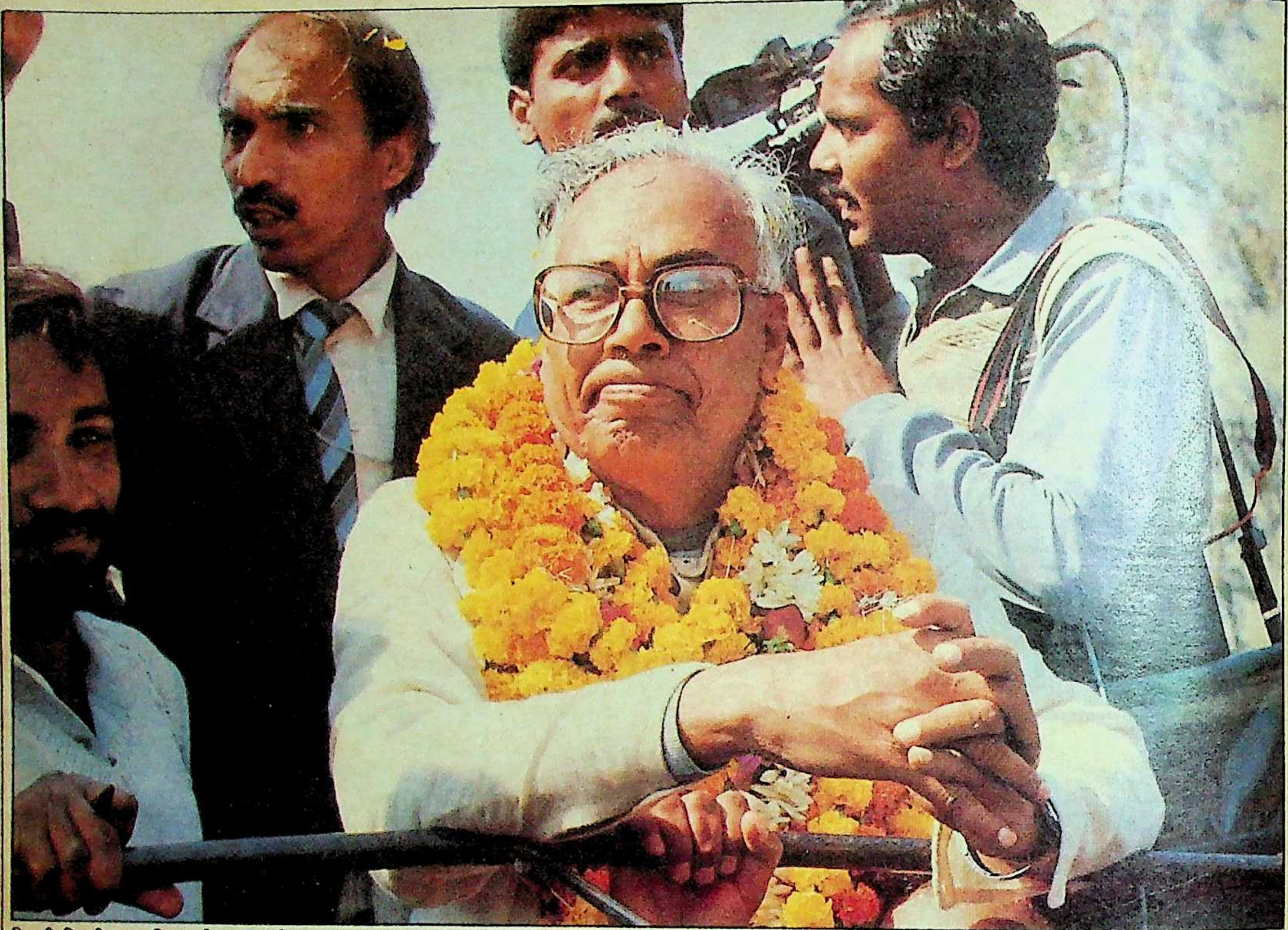

सिट्टी-पिट्टी गुम : बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद

छाया : दीपक कुमार

इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। लेकिन आज हालात बदल गये हैं। गुजरात में अहमद पटेल की अमर सिंह चौधरी से नहीं पटती, तो माधव सिंह सोलंकी आमादा हैं कि चौधरी को किसी भी तरह चैन न लेने दिया जाये। बताया जाता है कि बूटा सिंह और फोतेदार अमर सिंह चौधरी को चाहते हैं, लेकिन वहां की प्रभारी पार्टी महासचिव शीला कौल उन्हें नहीं चाहतीं। इसी तरह राजस्थान में बूटा सिंह और गुलाम नबी आजाद, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत के तरफदार बताये जाते हैं, तो चर्चा है कि शीला दीक्षित और फोतेदार उनके खिलाफ हैं। बताया जाता है कि शीला दीक्षित की अशोक गहलोत से तीखी झड़प भी हो चुकी है। जयपुर में शांति की संभावना इसलिए भी नजर नहीं आती, क्योंकि वहां राजेश पायलट के अपने स्वार्थ हैं। जम्मू-कश्मीर में फोतेदार और गुलाम नबी आजाद के अपने अलग-अलग गुट हैं और दोनों गुट एक दूसरे का गला काटने के लिए जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में गुलाम नबी आजाद किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वे इसी प्रदेश से चुनकर राज्य सभा में भेजे गये हैं। अन्य केंद्रीय पर्यवेक्षक एक ओर शरद पवार तो दूसरी ओर एसबी चह्वाण और एनएम तिरपुडे के गुटों में बंट चुके हैं। एक पक्ष राजीव गांधी को बता रहा है कि शरद पवार दरअसल कांग्रेस-इ की नहीं कांग्रेस-एस की सरकार चला रहे हैं, तो दूसरा गुट दावा कर रहा है कि एसबी चह्वाण और वसंत दादा पाटील अपने-अपने स्वार्थों के लिए महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने की जुगाड़ में लगे हैं। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि बूटा सिंह अर्जुन सिंह से नफरत करते हैं, जबकि फोतेदार को अर्जुन सिंह का समर्थक करार दिया जाता है।

गैरइंका प्रदेश में भी : कांग्रेसी नेताओं की यह गुटबाजी गैरकांग्रेस शासित हरियाणा में भी अपना रंग दिखा रही है, जहां दो 'लाल' (बंसीलाल और भजनलाल) एक दूसरे से टकराव की स्थिति बनाये हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस-इ विधायक रंगाराव की हत्या को भुनाने के लिए पी शिवशंकर हैदराबाद दौड़े-दौड़े गये और बजाय कांग्रेस-इ को फायदा पहुंचाने के जातीय संघर्ष बढ़ाकर कांग्रेस-इ को बदनाम करके चले आये। एडीटर्स गिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में पी शिवशंकर की इस भूमिका की बेहद भर्त्सना की है। इससे न केवल आंध्र प्रदेश में,

> **गुजरात में अहमद पटेल की अमर सिंह चौधरी से नहीं पटती, तो माधव सिंह सोलंकी आमादा हैं कि चौधरी को किसी भी तरह चैन न लेने दिया जाये। बताया जाता है कि बूटा सिंह और फोतेदार अमर सिंह चौधरी को चाहते हैं, लेकिन वहां की प्रभारी पार्टी महासचिव शीला कौल उन्हें नहीं चाहतीं। इसी तरह राजस्थान में बूटा सिंह और गुलाम नबी आजाद, शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत के तरफदार बताये जाते हैं, तो चर्चा है कि शीला दीक्षित और फोतेदार उनके खिलाफ हैं।**

बल्कि सारे देश में कांग्रेस-इ की यह छवि बनी है कि राजीव गांधी के लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं।

विभिन्न प्रदेशों में व्याप्त वर्तमान राजनीतिक संकट के दौर में सारे असंतुष्ट और विरोधी गुट राजीव गांधी के सलाहकारों के आपसी सत्ता-संघर्ष से ही शह और सहायता प्राप्त कर रहे हैं। बताया जाता है कि फोतेदार के व्यवहार से बूटा सिंह खिन्न हैं, तो बूटा सिंह के खिलाफ फोतेदार का कहना है कि उन्हें भारत के उत्तरी क्षेत्र के प्रदेशों की राजनीतिक संस्कृति की समझ नहीं है और उन्होंने अपने व्यवहार से असंतोष को और गहरा किया है। गुलाम नबी आजाद का अपना कोई मजबूत आधार नहीं है और उन्हें यह कतई पसंद नहीं है कि विभिन्न प्रदेशों की कांग्रेस इकाइयों के मामले में शीला कौल की चले। शीला दीक्षित भी दुखी हैं, क्योंकि उन्हें भी राजीव के दरबारियों ने सत्ता के खेल में घसीट लिया है। इस प्रकार राजीव के इन खासमखास लोगों के बीच आपसी लड़ाई उग्र होती जा रही है, क्योंकि इन लोगों का अपना कोई आधार नहीं है और ये सभी भयभीत हैं कि न जाने कब उन्हें सत्ता से दूर कर दिया जाये। जगन्नाथ मिश्र का बिहार में, माधव सिंह सोलंकी का गुजरात में और वीर बहादुर सिंह का उत्तर प्रदेश में कुछ आधार जरूर है, लेकिन इनके अपने-अपने स्वार्थ भी हैं और वीर बहादुर को छोड़कर इनका राजीव गांधी से सीधा संपर्क भी नहीं है।

तीन तेरह : सलाहकारों की समन्वित और स्पष्ट कार्यप्रणाली न होने के कारण पार्टी में तरह-तरह के भ्रम फैलते हैं और बेवजह स्थिति जटिल हो जाती है। उदाहरणार्थ अर्जुन सिंह जिस विमान से अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देने के लिए दिल्ली से भोपाल रवाना हुए थे, उसी विमान में दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। दिल्ली से किसी ने इस बीच फोन करके भोपाल स्थित विधायकों को सूचना दी कि अर्जुन सिंह त्यागपत्र दे रहे हैं और उनके साथ दिग्विजय सिंह तथा प्रधानमंत्री के केंद्रीय पर्यवेक्षक गुलाम नबी आजाद भी भोपाल पहुंच रहे हैं। इससे अधिकांश विधायकों को यह मुगालता हुआ कि आलाकमान अर्जुन सिंह के स्थान पर दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में उस वक्त यह सवाल सरगर्म था कि आजाद को किसने अर्जुन सिंह के साथ भोपाल जाने की सलाह दी थी, जबकि विभ्रम में पड़े मोतीलाल वोरा ७ रेसकोर्स रोड में बैठे अगले आदेशों की

फिर से सक्रिय : माखन लाल फोतेदार

इन घर फूंक चिरागों से मुक्ति पाने के लिए राजीव ने पुराने चावलों को फिर से कांग्रेस की हंड़िया में डालना शुरू कर दिया। आरके धवन की वापसी इसी का संकेत है। देखना है इस बदलाव की प्रक्रिया से राजीव गांधी कांग्रेस की आग को बुझाने में कितने सफल होते हैं।

आखिर बुलाना पड़ा : विशेष कार्य अधिकारी आरके धवन राजीव गांधी के साथ

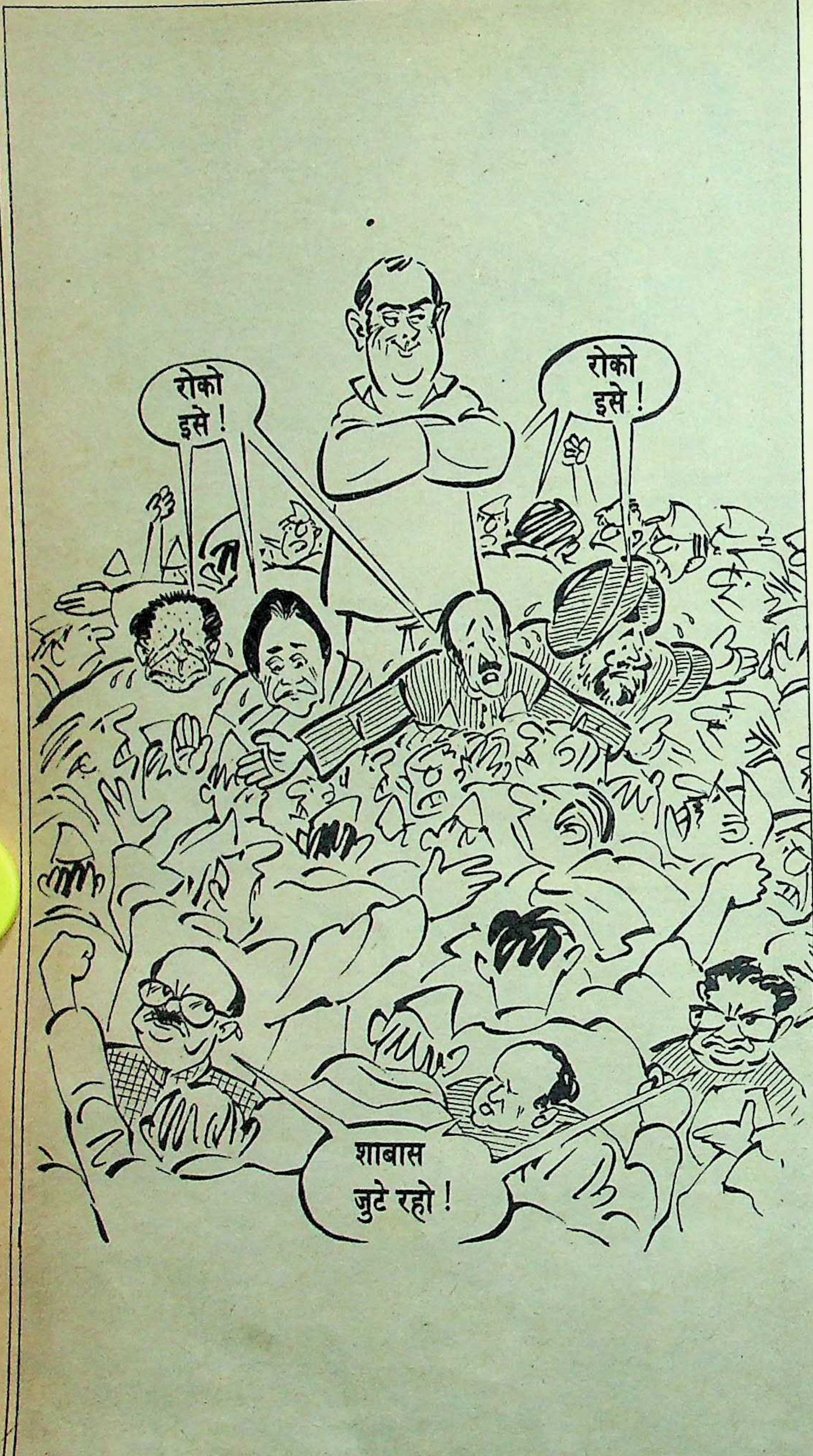
रोको इसे !
रोको इसे !
शाबास जुटे रहो !

प्रतीक्षा कर रहे थे। इस संबंध में अनेक अटकलें हवा में उछलीं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री का दावे के साथ कहना था कि आजाद को यह सलाह फोतेदार ने दी थी। बताया जाता है कि इन्हीं मंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा था कि फोतेदार की अरुण नेहरू से साठगांठ है और इसी कारण वे पार्टी में संकट उत्पन्न करने में जुटे हुए हैं। इस तरह जहां कांग्रेस शासित विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में कांग्रेसी नेता आपस में जूझ रहे हैं, वहीं दिल्ली में राजीव गांधी के सलाहकार भी आपस में भिड़े हुए हैं।

यहां तक कि लखनऊ में भी राजीव गांधी के लोगों में व्याप्त मतभेदों के खतरनाक परिणाम सामने आने लगे हैं। जो तीन सदस्यीय केंद्रीय दल असंतुष्टों को दबाने के लिए भोपाल गया था, उसमें वीर बहादुर सिंह भी शामिल थे, जबकि लखनऊ में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुटबाजी चल रही है। इस प्रकार जो लोग किसी प्रदेश की गुटबाजी को समाप्त करने के लिए भेजे जाते हैं, वे किसी दूसरे प्रदेश में गुटबाजी को बढ़ावा देने के कारण भी बन रहे हैं।

लखनऊ में भी राजीव गांधी के लोगों में व्याप्त मतभेदों के खतरनाक परिणाम सामने आने लगे हैं। जो तीन सदस्यीय केंद्रीय दल असंतुष्टों को दबाने के लिए भोपाल गया था, उसमें वीर बहादुर सिंह भी शामिल थे, जबकि लखनऊ में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुटबाजी चल रही है।

ऐसी हालत में इस बात की बहुत कम संभावना नजर आती है कि संशय और दुविधा से ग्रस्त राजीव गांधी फटी कांग्रेस को सिलने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि कुछ बिचौलियों का धंधा काफी फलफूल रहा है। वे राजीव गांधी के सलाहकारों के निर्देश पर असंतुष्टों और मंत्रियों के बीच तरह-तरह के किस्सों और अफवाहों का जमकर प्रचार कर रहे हैं। स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो क्या घर के चिरागों से ही कांग्रेस के घर को स्वाहा होने से कोई बचा सकता है? इन घर फूंक चिरागों से मुक्ति पाने के लिए राजीव ने पुराने चावलों को फिर से कांग्रेस की हंडिया में डालना शुरू कर दिया। आरके धवन की वापसी इसी का संकेत है। देखना है इस बदलाव की प्रक्रिया से राजीव गांधी कांग्रेस की आग को बुझाने में कितने सफल होते हैं।

— ब्यूरो रिपोर्ट / अभय अग्रवाल

सत्ता की ओर बढ़ते विपक्ष को क्या राजीव रोक पायेंगे ?

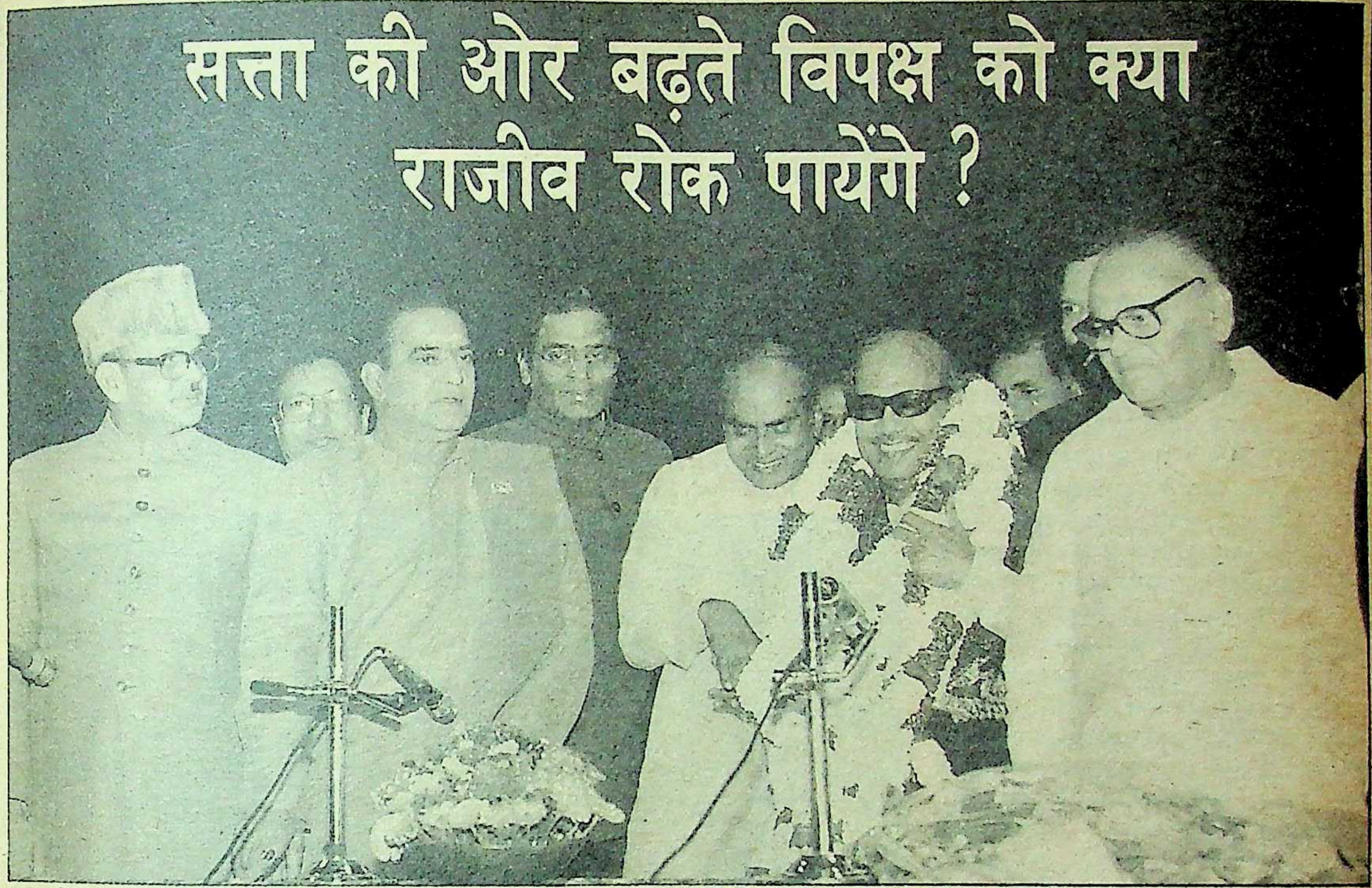

राष्ट्रपति भवन का रास्ता : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को दिल्ली में बधाई देते समय (बायें से) वीपी सिंह, रामाराव, अजीत सिंह और एसआर बोम्मई

तमिलनाडु में द्रमुक-राज की वापसी के साथ ही जहां राजीव गांधी, उनकी पार्टी और सरकार पर ग्रहण लगने के आसार दिखायी देने लगे हैं, वहीं विपक्ष ने जरूरत से भी ज्यादा बुलंद हौसले से केंद्रीय सत्ता के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। इसका सबब क्या है ? और इसका अंजाम ?

सत्तारूढ़ दल के घर में आग लगी हो, तो विपक्ष का कलेजा ठंडा होना स्वाभाविक है। विपक्ष इतना मगन है कि वह आगामी चुनावों में कांग्रेस-इ को हरा कर प्रधानमंत्री कार्यालय पर ही नहीं, राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा करने की बात खुलेआम करने लगा है। हाल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई ने दिल्ली में कहा, "कांग्रेस आज ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। इसका सबसे बड़ा श्रेय श्री करुणानिधि को है। आज मैं उनको बधाई आंध्र भवन में दे रहा हूं। अगली बार मुझे आशा है, मैं उनको यह बधाई राष्ट्रपति भवन में दूंगा।"

अब देवीलाल के साथ : चंद्र शेखर

आत्मविश्वास : विपक्ष का हौसला बढ़ाने में तमिलनाडु की जीत का तो प्रमुख हाथ है ही, साथ ही इस चुनाव के बाद विभिन्न राज्यों में इंका में छिड़े महाभारत ने भी विपक्ष के आत्मविश्वास को सघन किया है। यद्यपि करुणानिधि की जीत का मूल कारण यह नहीं है कि उनकी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम राष्ट्रीय मोर्चे का अंग है, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चे को यह दम भरने का बहाना मिल गया है कि जनता ने राष्ट्रीय मोर्चे को गले लगा लिया है और कांग्रेस-इ को ठुकरा दिया है। तमिलनाडु के चुनाव के बाद विपक्ष ने बार-बार कहा है कि राजीव गांधी हार के प्रतीक हैं और राष्ट्रीय मोर्चा विजय का पर्याय। इस सबल प्रचार का विपक्ष को फायदा भी मिला है। राष्ट्रीय मोर्चे की फतह की डमडमी बजने से कांग्रेस-इ के सदस्यों ने अपने-अपने राज्य में 'मुख्यमंत्री बदलो' अभियान के तहत पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के वर्चस्व को परोक्ष चुनौती देना शुरू कर दिया है।

एकता का प्रदर्शन : कांग्रेस-इ में पड़ी इस फूट का फायदा उठाने के लिए विपक्ष ने अपनी एकता की मजबूती का प्रदर्शन करना तुरन्त शुरू कर दिया, ताकि जनता को लगे कि वह कांग्रेस-इ का बेहतर विकल्प है। इसका प्रमाण है तमिलनाडु की जीत के दो दिन बाद २८ फरवरी को कलकत्ता में आयोजित

गैरइंका मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन का यों तो मुख्य उद्देश्य केन्द्र से राज्यों के लिए और अधिकार प्राप्त करने के लिए मुहिम शुरू करना था, लेकिन इसके साथ आम जनता तक यह संदेश भी पहुंचाना था कि जहां कांग्रेसी मुख्यमंत्री जनता और प्रशासन को भूल कर अपनी कुरसी बचाने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं, वहां गैरइंका मुख्यमंत्री स्थिर हैं, उनकी कुरसी किसी आलाकमान की दया की मोहताज नहीं है और उनका ध्यान केन्द्रित सत्ता को विकेन्द्रित करके बेहतर व्यवस्था की स्थापना पर लगा है। कांग्रेस निरंतर यह आरोप लगाती रही है कि विपक्ष कभी स्थायी सरकार नहीं दे सकता। लेकिन इंका शासित राज्यों में मची अफरातफरी के बाद स्वयं विपक्ष ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस की कोई राज्य सरकार स्थिर नहीं, अल्प समय में एक मुख्यमंत्री उतरता है, तो दूसरा चढ़ता है, जबकि प्रत्येक गैरइंका सरकार टिकाऊ है। यद्यपि कर्नाटक में परिवर्तन हुआ है, लेकिन यह परिवर्तन आलाकमान की इकहरी इच्छा से नहीं, बल्कि विधायकों के लोकतांत्रिक बहुमत से हुआ है। कलकत्ता में वामपंथी मुख्यमंत्रियों सहित सपूर्ण गैरइंका मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद राष्ट्रीय मोर्चे के पांच मुख्यमंत्रियों ने ६ फरवरी को दिल्ली में बैठक की और ७१ सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने के लिए २१ सूत्री कार्ययोजना की संगेबुनियाद रखी। इस २१ सूत्री कार्ययोजना में भूमि सुधार, महिलाओं के लिए रोजगार में आरक्षण, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, बेरोजगारों के लिए यात्रा-सुविधा आदि कार्यक्रम रखे गये हैं, जो पिछड़े, शोषित और समाज के वंचित वर्ग के लिए फायदेमंद हैं। विपक्ष पर कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगता रहा है कि उसका एकसूत्री कार्यक्रम है, राजीव हटाओ। इसके विपरीत राष्ट्रीय मोर्चे के मुख्यमंत्रियों ने इस कार्ययोजना को रख कर यह सिद्ध करना चाहा है कि विपक्ष की एकता का लक्ष्य जनहित है और उसका एक समान कार्यक्रम है। १० फरवरी को दिल्ली में ही राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष मंडल की बैठक हुई और तय हुआ कि मोर्चे के सभी घटक समान घोषणापत्र पर चुनाव लड़ेंगे। इस समान घोषणापत्र की घोषणा करके मोर्चे ने इस आरोप को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है कि मोर्चे में शामिल दलों की क्षेत्रीय मानसिकता है, और वे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सोचते। दिल्ली के इन सम्मेलनों के बाद गुवाहटी में असम गण परिषद की ओर से ११ फरवरी को एक रैली का आयोजन हुआ। यह रैली एक प्रकार से असम में राष्ट्रीय मोर्चे की पहली रैली थी और इसमें एनटी रामाराव और देवीलाल सहित मोर्चे के कई नेताओं ने अपनी ध्येयनिष्ठ एकता का प्रदर्शन किया।

कांग्रेस में भगदड़ मचाने की कोशिश : कांग्रेस में बढ़ती खलबली से उत्साहित होकर विपक्ष ने अपनी एकता के पलस्तर को मजबूत करने की जो कोशिश शुरू की है, उससे यह भय भी हो गया है कि कुछ कांग्रेसी पार्टी के डूबते जहाज को देखकर विपक्ष के किनारे लगने की कोशिश करें। पर समस्या यह है कि विपक्ष उनका स्वागत तो करता है, लेकिन आगामी चुनावों में उन्हें टिकट देने का वचन नहीं देता। राष्ट्रीय मोर्चे के एक नेता के अनुसार, "टिकट पर पहला अधिकार उनका होगा जो लंबे समय से विपक्ष के साथ रहे हैं।" लेकिन एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के अनुसार, "टिकट की समस्या तो ठीक है। पर कुछ कांग्रेसियों का खुला स्वागत कर विपक्ष कांग्रेस में आतंक तो पैदा कर सकता है। विपक्ष के एक निमंत्रण पर कांग्रेस छोड़नेवालों की कतार लग जायेगी।" पर्यवेक्षक की टिप्पणी एक अतिशयोक्ति हो सकती है, पर सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस बात पर चिंता है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और बहुत से कांग्रेसी उसकी ओर आशा लगाये बैठे हैं। ऐसी भी सूचना है कि प्रधानमंत्री ने राज्यमंत्री शीला दीक्षित को एक गोपनीय रपट तैयार करने के लिए कहा है कि जिन सांसदों को टिकट दिये जा सकते हैं, उनकी सूची तैयार की जाये। पर कांग्रेस की जो अवस्था है, उससे यह नहीं लगता कि यह रपट गोपनीय रह पायेगी। यह निश्चित है कि जिन सांसदों को टिकट नहीं देने का विचार कांग्रेस नेतृत्व ने रखा, वे बगावत पर उतर आयेंगे। गुप्तचर सेवाओं के अनुसार पहले ही ५० से अधिक इंका सांसद विपक्ष के साथ संबंध बनाये हुए हैं और मौका लगते ही कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं।

समीकरण बदलेगा ? : विचार-विमर्श करते हुए (बायें से) अजीत सिंह, वीपी सिंह, देवीलाल और हेगड़े

यह पूछे जाने पर कि फूट तो विपक्ष में भी है और इसे भी रामधन, बहुगुणा, सुब्रह्मण्यम स्वामी, देवगौड़ा जैसे लोगों से नुकसान हो सकता है, जनता दल के एक नेता ने कहा, "जब कांग्रेस ही पतन पर है और स्वयं कांग्रेसी विपक्ष में आ रहे हैं, तो ये लोग कांग्रेस में जाकर क्या करेंगे? और यदि इन्हें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस में शामिल भी कर लिया, तो पुराने कांग्रेसियों को रास नहीं आयेंगे जो इनका आना अपने अधिकारों पर अतिक्रमण समझेंगे।"

अनेक राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत के बाद 'माया' ने पाया कि विपक्ष आगामी चुनावों में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और उसे विश्वास है कि उसका कोई बड़ा नेता इंका में नहीं जायेगा। एक विपक्षी नेता के अनुसार, "राजीव गांधी वोट जीतने में अक्षम हैं। न ही उनकी पार्टी के पास कोई नेता है जो कांग्रेस को सत्ता में ला सके।" इस नेता के अनुसार पूरा दक्षिण भारत, जहां से लोकसभा की १२६ सीटों के चुनाव होने हैं, कांग्रेस की पकड़ से पहले ही बाहर जा चुका है। परिणामस्वरूप इन राज्यों के अधिकतर कांग्रेसी नेताओं को यह डर है कि यदि वे कांग्रेस में बने रहे, तो चुनाव हार जायेंगे। अत: वे विपक्ष के साथ गठबंधन करने की फिराक में हैं, ताकि वे किसी भी प्रकार सत्ता में बने रह सकें। लगभग यही हालत अन्य राज्यों में है। हरियाणा में लोकदल (जनता दल) और इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह की विजय ने यह पहले ही साबित कर दिया है कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों में भी कांग्रेस की तूती अब नहीं बोलती। इसके बाद आया कांग्रेस में विद्रोह। पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम में पहले ही विपक्ष की सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के अनुसार, "कांग्रेस में विद्रोह का मूल कारण यह है कि राजीव गांधी न सिर्फ एक प्रशासक एवं कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से असफल रहे हैं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के लिए वोट पाने में भी असफल रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, सिक्किम और हरियाणा के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस की हार ने यह बात सिद्ध कर दी है।" यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस में असंतोष तमिलनाडु की हार के बाद ही क्यों फूटा, जनता दल के वरिष्ठ नेता ने

'माया' से कहा, ''असंतोष तो बहुत समय से था, पर कांग्रेसियों को आशा थी कि राजीव गांधी अपनी शैली सुधार लेंगे और किसी एक कार्यक्रम को लेकर चुनाव जीत सकेंगे। पर तमिलनाडु की हार के बाद उनकी सभी आशाओ पर पानी फिर गया है।'' असम गण परिषद के नेता दिनेश गोस्वामी के अनुसार तमिलनाडु चुनाव का असर इसलिए भी बहुत अधिक हुआ, क्योंकि ''प्रधानमंत्री अपने पैसे की शक्ति, ताकत, गवर्नर पद तथा अन्य सरकारी संस्थाओ एवं दूरदर्शन मीडिया के भारी दुरुपयोग के बावजूद १३ वर्ष तक सत्ता से बाहर रही द्रमुक से चुनाव हार गये।'' द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमत्री करुणानिधि के अनुसार, ''प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने का भरसक प्रयत्न किया और तमिलनाडु की १३ बार यात्रा की, लेकिन मैं फिर भी १३ साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद वापस आ गया।''

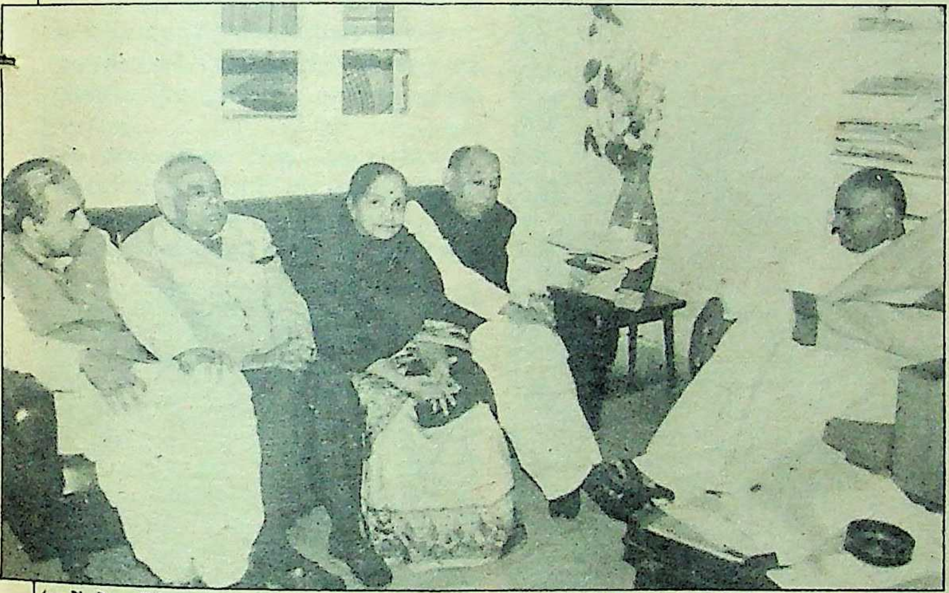

'जायें तो जायें कहां ? : देवगौड़ा (सबसे बायें), स्वामी, शहाबुद्दीन, सरोजिनी महिषी और इंदुभाई पटेल

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लखनऊ में कहा है कि चुनाव समय पर होंगे। अधिकांश विपक्षी नेता भी इस बात से सहमत हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता के अनुसार, ''यदि चुनाव स्थगित किये गये, तो कांग्रेसी भी इसका विरोध करेंगे।''

सभी विपक्षी दल अब चुनावी तैयारियों और चुनावी समीकरण बनाने में जुट गये हैं। राष्ट्रीय मोर्चे के सभी घटक पार्टियों ने एक ही घोषणापत्र पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया है और घोषणापत्र तैयार करने के लिए सुरेन्द्र मोहन के नेतृत्व में एक कार्यसमिति भी गठित कर दी है। माकपा का चुनावी कार्यक्रम त्रिवेंद्रम में हुई कांग्रेस में तय किया जा चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगले माह होनेवाली कांग्रेस में अपने घोषणापत्र को तैयार करेगी। भाजपा का घोषणापत्र लगभग तैयार है।

विपक्षी दलों के चुनावी समीकरण भी बनने लगे हैं और विपक्षी पार्टियों के मध्य विवाद इस बात पर गौण हो चले हैं कि राजीव गांधी की हार अब सामने है और इस हार को साकार बनाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जनता दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुसार, ''आज की परिस्थितियों में राजीव हटाओ एक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम है।''

विपक्ष को फायदे : कांग्रेस में बगावत के बाद विपक्ष कुल मिला कर निम्नलिखित मुद्दों को प्रचारित करके अपने को बेहतर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्थापित कर सकता है।

० राजीव गांधी निरंतर चुनाव हारते जा रहे हैं, जबकि विपक्ष निरंतर कांटे के चुनाव जीत रहा है। इलाहाबाद के बाद तमिलनाडु की जीत का दृष्टांत दिया जा सकता है।

० राजीव गांधी अपनी पार्टी को बांधे रखने में असफल हो रहे हैं, जबकि विपक्ष दिनोदिन और मजबूती से बंधता जा रहा है। सभी गैरइंका मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन और समान घोषणापत्र इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष एनटी रामाराव ने बजट की सूचना रिसने के कारण अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल को बदल कर नया मंत्रिमंडल बना लिया और पार्टी में किसी ने चूं तक नहीं की, जबकि कांग्रेस का कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो आलाकमान की इच्छा के बिना मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री ले सके या निकाल सके।

० राजीव गांधी की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण धूमिल हो चुकी है, जबकि विपक्षी नेताओं पर लगाये गये आरोप कपूर की तरह उड़ रहे हैं।

० राजीव गांधी आदेशों का पालन न करनेवालों को पार्टी से निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन जनता दल ने सुब्रह्मण्यम स्वामी, रामधन, बहुगुणा और देवगौड़ा से पल्ला छुड़ाने में तनिक भी देर नहीं की।

० कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार स्थिर नहीं, लेकिन विपक्ष की हर सरकार सुस्थिर है और हर मुख्यमंत्री का अपने विधायकों पर अक्षत वर्चस्व है।

विपक्ष की कमजोर नस : लेकिन इसका मतलब यह नहीं है विपक्ष पूर्णतया निरापद हो गया है। राष्ट्रीय मोर्चे के स्तर पर तो मामला ठीक-ठाक है, लेकिन इसके एक घटक जनता दल के प्रांतीय अध्यक्षों, खासकर मप्र, उप्र, बिहार और राजस्थान पार्टी अध्यक्षों के चयन में जिस तरह की खींचतान दिखायी दी है, उससे पार्टी में घटकवाद के उभरने के पूरे आसार हैं। दूसरी ओर जनता दल के वरिष्ठ नेताओं के आपसी समीकरण दिनोदिन बदल रहे हैं। वीपी सिंह और देवीलाल कभी दो शरीर एक प्राण थे, लेकिन प्रांतीय अध्यक्षों के चुनाव को लेकर वे वीपी सिंह के बजाय चंद्रशेखर के करीब हुए हैं और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित करने के बाद अब कहने लगे हैं कि किसान का बेटा प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री का चयन चुनाव के बाद सांसद करेंगे। ये बदले हुए स्वर इस बात का संकेत देते हैं कि जनता दल में घटकवाद का इलाज आसान नहीं। विपक्ष में भाजपा एक शक्ति है और उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के नतीजे, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के हटने और शिवसेना का भाजपा की ओर बढ़ता हाथ भाजपा के सकारात्मक पहलू हो गये हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा अपनी शर्तों पर ही राष्ट्रीय मोर्चे से गठबंधन करना चाहेगी। इन शर्तों के कारण यदि अचूक गठबंधन नहीं हो सका, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में विपक्ष के वोट बिना बंटे नहीं रह सकते।

यदि राजीव गांधी तुरन्त चुनाव की घोषणा करते हैं, तो टिकटों के लिए जनता दल में मारामारी हो सकती है और अभी जो विपक्ष मजबूत धरातल पर दिखायी देता है, वह उनके पांवों के नीचे से खिसक सकता है। लेकिन यदि चुनाव निश्चित समय पर होते हैं, तो कांग्रेस में बेचैनी बढ़ती जायेगी और विपक्ष अपने को सत्ता के करीब समझ कर छोटे-मोटे मतभेदों को पाटने में कमोबेश सफल हो सकता है। पिछले साढ़े चार सालों से राजीव गांधी ने अपने नौसिखिए सलाहकारों के कारण जो कुछ खोया है, उसको पाने के लिए अपनी मां के परखे हुए आरके धवन जैसे व्यक्तियों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। सुलझे हुए सलाहकारों की सलाह पर चल कर अगर राजीव गांधी ने इस विद्रोह को तत्काल दबाने में सफलता पा ली और चुनाव की तुरन्त घोषणा कर दी, तो शायद सत्ता की ओर बढ़ते विपक्ष के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा सकती हैं। अन्यथा फिलहाल विपक्ष पूर्णतया अपने को विजय के समीप महसूस कर रहा है।

—ब्यूरो रिपोर्टों के साथ अभय अग्रवाल

धवन की वापसी का अर्थ

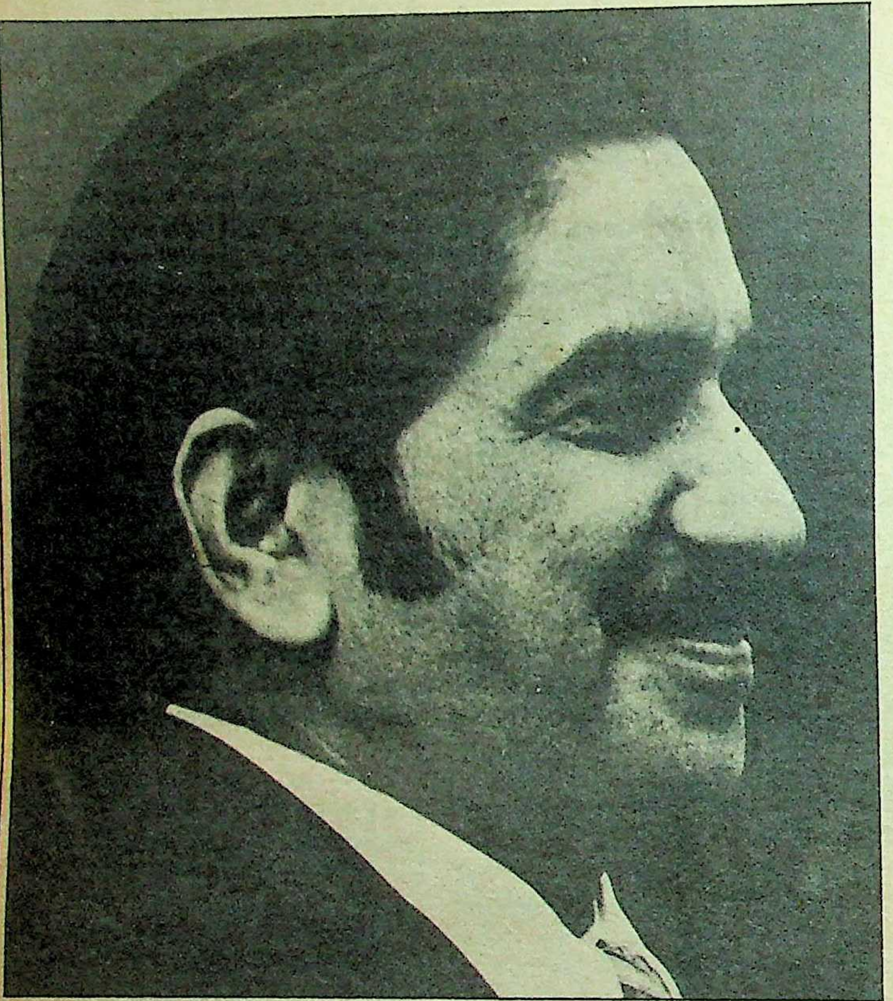

**दो दशकों तक
श्रीमती गांधी के विश्वस्त रहे आरके धवन को
राजीव गांधी ने सत्ता में आते ही
बाहर कर दिया था, लेकिन अब साढ़े चार साल बाद
उनको वापस लेने की आवश्यकता
क्यों पड़ गयी ?**

जाड़े के दिनों की एक अंधकारमय रात थी वह, जब दो दशकों तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अतिविश्वासपात्र सहायक रहे राजेंद्र कुमार धवन को प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने के लिए कई घंटे तक बाहर कार्यालय में प्रतीक्षा करनी पड़ी और जब वे कार्यालय से बाहर आये, तो उनकी कार को इंडिया गेट पर रोक कर उनका परिचय पत्र उनसे ले लिया गया।

दूसरी रात वह आयी जब शीला कौल के निवास स्थान पर एक पार्टी में अचानक धवन का सामना राजीव गांधी से हो गया और अनेक उपस्थित लोगों के सामने गांधी चल कर धवन के पास गये और उनका हालचाल पूछा।

तीसरी रात वह थी, जब धवन को सादर ७, रेसकोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री निवास पर बुलाया गया तथा राजीव गांधी ने १२ मिनट की बातचीत में चार वर्षों की दूरी समाप्त कर दी।

चौथी रात १८ फरवरी, १९८९ की थी जब धवन को अचानक सूचना मिली कि उन्हें कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निष्ठा काम आयी : फरवरी १९८५ और फरवरी १९८९ के बीच बीते चार सालों में दिल्ली की यमुना में अथाह पानी बहा और राजनीतिक पटल पूरी तरह बदल गया। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हारी और राजीव गांधी के अनेक सहायक और विश्वासपात्र या तो विपक्ष से जा मिले या हटा दिये गये। दूसरी ओर अनेक अपमानजनक घटनाओं के बावजूद राजेंद्र कुमार धवन गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान रहे। वर्तमान पद पर नियुक्ति केबाद धवन ने कहा, "मुझे मालूम था वफादारी ही काम आयेगी।" पर गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा १९८५ के आरंभ में तब काम नहीं आयी, जब उन्हें २२ वर्षों तक गांधी परिवार की सेवा करने के लिए धन्यवाद कहे बिना पदच्युत कर दिया गया तथा बाद में अपमानजनक रूप से झूठ पकड़ने वाले यंत्र

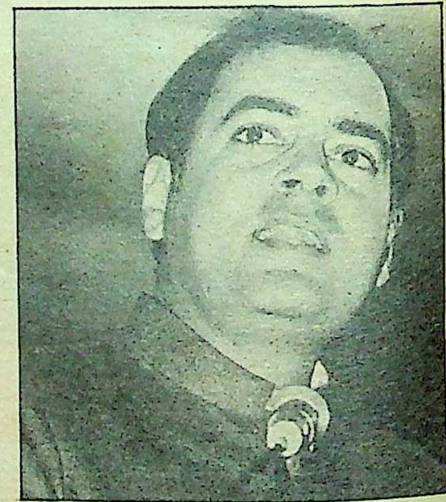

पुरानी बैसाखियों का सहारा : राजीव गांधी

का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। पर कहा जाता है , "२२ वर्ष तक इंदिरा गांधी के साथ रहे धवन को जितनी जानकारी राजनीति और राजनीतिज्ञों के बारे में है, उतनी किसी और को नहीं।धवन को अंदेशा था कि राजीव गांधी अपनी शैली और अगंभीर सहायकों के बल पर अधिक दिन नहीं चल पायेंगे और एक दिन उन्हीं का दामन थामेंगे। इसी आशा में वे हर अपमान को सहते रहे और राजीव गांधी के खिलाफ कभी अपना मुंह नहीं खोला।"

यह भी कहा जा रहा है कि धवन की वापसी में अमिताभ बच्चन और धीरुभाई अंबानी का हाथ है। यह संयोग ही है कि धवन की नियुक्ति के तीन दिन पहले अमिताभ बच्चन के एक करीबी मित्र दिल्ली के ताजमहल होटल में बतिया रहे थे कि किस प्रकार राजीव गांधी अपनी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं, "धवन को वापस लाकर, सरला ग्रेवाल को गवर्नर बना कर और शीला दीक्षित को राजनीतिक मामलों से हटाकर।" पहली दो बातें तो पूरी हो गयी हैं और अफवाह है कि तीसरी बात भी शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

धवन के पक्षधर : अमिताभ बच्चन

कार्य की छूट : पर ऐसी भी अफवाह है कि इस बार धवन को उतनी छूट नहीं दी जायेगी, जितनी इंदिरा गांधी के समय में थी। इस बार प्रधानमंत्री के तीनों मुख्य सलाहकार शीला दीक्षित, फोतेदार और बूटा सिंह धवन के विरोध में हैं और इस बात पर अड़े हैं कि धवन के पांव न जमने दिये जायें। ऐसी भी सूचना है कि धवन के पास ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं, जिनके आधार पर वे बिहार में जगन्नाथ मिश्र, गुजरात में ज़िनाभाई दारजी, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह तथा अन्य राज्यों के असंतुष्टों को सीमा लांघने से रोक सकते हैं तथा विपक्ष में शामिल हुए विद्याचरण शुक्ल जैसे अपने पुराने साथियों को विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन करने से रोक सकते हैं। पर इस जानकारी का उपयोग वे तभी करेंगे, जब उन्हें पहले जैसी छूट दी जाये और उन पर पूरा भरोसा किया जाये। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के अनुसार, "धवन इंदिरा गांधी के कान, आंख और हाथ सभी कुछ थे। श्रीमती गांधी उनकी सलाह कभी नहीं टालती थीं। पर कोई भी राजनीतिक कदम वे धवन को बिना बताये नहीं उठाती थीं। यदि राजीव गांधी धवन को पूरी तरह विश्वास में नहीं लेंगे, तो धवन को पूरी जानकारी नहीं होगी और वे ठीक सलाह नहीं दे पायेंगे।" एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के अनुसार, "धवन को लाने का राजीव गांधी का निर्णय ठीक है। पर बहुत देर हो चुकी है। जब तक दोनों के बीच पूरा विश्वास कायम होगा, तब तक चुनाव आ चुके होंगे।"

शैली बदलने की आवश्यकता : अनेक कांग्रेसी और विपक्षी नेताओं से बात करने के बाद 'माया' ने पाया कि यदि राजीव गांधी धवन को लाकर भी अपनी पुरानी शैली बनाये रखेंगे, तो धवन की वापसी का कुछ खास लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला। लगभग सभी राजनीतिज्ञों को आशंका है कि "राजीव गांधी धवन की बात तो सुनेंगे, पर करेंगे मनमानी।" एक भूतपूर्व कांग्रेसी नेता जो अब विपक्ष में हैं ने कहा, "श्रीमती गांधी धवन की राय के बिना मंत्री भी नहीं बदलती थीं। यहां तक कि १९८३ में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हुई भारी हार के बाद उन्होंने राजीव गांधी की यह सलाह ठुकरा दी कि प्रणब मुखर्जी, भीष्म नारायण सिंह तथा चार अन्य मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाये। कारण धवन की यह सलाह थी कि इन लोगों के निकाले जाने से पार्टी में असंतोष फैलेगा।" पर क्या राजीव गांधी धवन को इतनी अधिक छूट दे पायेंगे ?

सत्ता केंद्र से बाहर : सरला ग्रेवाल

राजनीतिक
आकांक्षा पर
अंकुश :
गोपी अरोड़ा

एक कांग्रेसी के अनुसार, "राजीव गांधी किसी पर भी विश्वास करने में असमर्थ हैं। उनके पास सूचना है कि फोतेदार के भाई शरद यादव के घर पर केसी त्यागी से अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। बूटा सिंह और शीला दीक्षित हर राज्य में अपना गुट तैयार कर रहे हैं। अविश्वास का कारण भूतपूर्व विश्वासपात्रों (अरुण नेहरू और विश्वनाथ प्रताप सिंह) का विपक्ष में चला जाना भी है।" पर दूसरी ओर अरुण सिंह का उदाहरण भी है जो सत्ता से निकाले जाने के बाद भी गांधी के प्रति निष्ठावान रहे। स्वयं राजेंद्र कुमार धवन ने अनेक अपमान सहने के बावजूद गांधी के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला। एक सांसद के अनुसार, "राजीव गांधी समझ गये हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जो दोस्त थे, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, जिन्हें दुश्मन समझा गया, उन्होंने दोस्ती निभायी। कोई कारण नहीं कि गांधी धवन पर पूरा विश्वास न करें।"

पर यह शायद अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है कि धवन को प्रधानमंत्री कार्यालय में न लेकर काबीना सचिवालय में लिया गया है। शायद सचिवालय से ही धवन गांधी के सलाहकार और प्रबंधक का काम करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सूत्र के अनुसार, "धवन ने गांधी के समक्ष दो ही शर्तें रखीं। एक तो यह कि वे सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क करेंगे। दूसरी यह कि बूटा सिंह, फोतेदार आदि लोगों को हटाया जाये। उनकी दोनों शर्तें मान ली गयी हैं।"

यह भी एक संयोग ही है कि धवन की वापसी से दून स्कूल के साथियों सहित अब तक प्रधानमंत्री के करीबी सभी सलाहकारों में भय व्याप्त है। यहां तक कि धवन की नियुक्ति के बाद अगले दिन सभी समाचारपत्रों ने खबर को ऐसे उछाला मानो उपप्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई हो। स्वयं धवन के घर पर राजनीतिज्ञों का तांता लग गया।

पर धवन की सफलता अभी भी विवाद का विषय है। एक विपक्षी सांसद के अनुसार, "पहले धवन सक्षम थे, क्योंकि इंदिरा गांधी सक्षम थीं। अब जब राजीव गांधी ही कमजोर हैं, तो धवन किस प्रकार उन्हें उबार पायेंगे?"

एक सूत्र के अनुसार यह निर्णय लिया जा चुका है कि कांग्रेस की सभी फाइलें धवन के हाथों से गुजरेंगी और हर विषय पर उनकी सलाह ली जायेगी। अपनी छवि को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ने गोपी अरोड़ा को वित्त मंत्रालय में नियुक्त किया है, ताकि वह वामपंथी और लोकप्रिय बजट पेश कर सकें। नौकरशाहों के राजनीतिक प्रयोग की शैली शायद राजीव गांधी ने नहीं बदली है, पर सार बदल गया है।

—विशेष प्रतिनिधि

९० प्रतिशत हिंदी फिल्में पिटीं

वर्ष १९८८ में हिंदी की १४० फिल्में प्रदर्शित हुई जिनमें से ९० प्रतिशत फिल्में पिट गयीं। फिल्म वितरकों ने पाबंदी लगायी है कि कोई भी फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री १२ से अधिक फिल्मों में काम नही कर सकेगा, लेकिन दिसंबर, १९८८ के अंतिम दो हफ्तों में ही १३० नयी फिल्मों का मुहूर्त हुआ, जिनमें मुख्य रूप से वे फिल्मी सितारे काम कर रहे हैं, जिनके पास पहले ही तीस-तीस फिल्में हैं।

पिछले चार वर्षों में भारत में फिल्म निर्माण में लगातार कमी आ रही है। १९८५ में विभिन्न भारतीय भाषाओं की कुल मिलाकर ९१२ फिल्में बनी थीं, १९८६ में ८४०, १९८७ में ८०६ और १९८८ में ७७३ फिल्में बनीं।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष १९८७-८८ के दौरान अपने ३५ मंत्रियों पर कुल ७३ लाख ४४ हजार रुपए खर्च किये। इस खर्चे का रोचक पक्ष यह है कि मंत्रियों ने अपने वेतन से दुगुना खर्च अपनी यात्राओं पर किया। इनके वेतन के मद में जहां २३१४६९१ रुपए खर्च हुए, वहीं यात्रा भत्ते के रूप में ५०२९९३३१ रुपए का भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने १९८९-९० के बजट में प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है, लेकिन इस बजट में दर्शाये गये १५७.०३ करोड़ रुपए के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार करचोरों से राजस्व वसूलने की योजना बना रही है।

भारत में वैज्ञानिक ऐसा कंप्यूटर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिसके सामने जो कुछ भी बोला जायेगा, वह तुरंत टाइप हो जायेगा। इस कंप्यूटर से सर्वाधिक लाभ पत्रकारों को होगा, जिन्हें अभी अपनी रिपोर्टों को लिखना या टाइप करना पड़ता है।

वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि आज का मनुष्य जीवनयापन के लिए दांत पर निर्भर नहीं है और सभ्यता के विकास के साथ-साथ यह निर्भरता निरंतर कम होती रही। इस कारण उसके दांत भी छोटे होते जा रहे हैं। मानवशास्त्रियों के अनुसार मनुष्य के दांत का आकार प्रति एक हजार वर्ष में एक प्रतिशत छोटा होता गया है। एक लाख साल पूर्व के मुकाबले आज मनुष्य के दांतों का आकार आधा रह गया है।

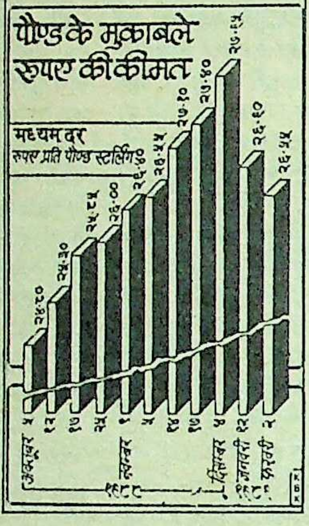

१६ फरवरी को घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार श्रीलंका की २२५ सदस्योंवाली नयी संसद में सत्तारूढ़ यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने १२५ स्थान प्राप्त करके स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। उसकी प्रमुख विरोधी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को ६७ सीटें और तमिल संगठनों को मात्र २३ सीटें हासिल हो सकी हैं। श्रीलंका की संसद के २२५ सदस्यों में से ९६ सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि बाकी २९ जगहों का फैसला पार्टियों को मिले वोटों के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

श्रीलंका में मतदान के दिन ही ६७ लोग मारे गये थे और पांच हफ्तों के चुनाव-प्रचार के दौरान एक हजार से अधिक लोगों की हत्याएं हुईं, जिनमें १४ प्रत्याशी और तीन सौ राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

जापानी एक ऐसा माइक्रो रोबोट (यांत्रिक प्राणी) बनाने में जीजान से जुटे हैं जो शरीर में घुसकर रोगग्रस्त हिस्सों का पता लगायेगा और उनका इलाज करके बाहर आ जायेगा। जापानियों को उम्मीद है कि वे वर्ष १९८९ के अंत तक इस सूक्ष्म रोबोट का निर्माण करने में सफल हो जायेंगे।

केरल उच्च न्यायालय ने एक ऐसी याचिका पर विचार करना स्वीकार कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि जब एक नागरिक को जीने का अधिकार है, तो उसे मरने का भी अधिकार होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याण सिंह के अनुसार भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर कब्जे की घटनाओं को रोकने के लिए एक लाख कार्यकर्ताओं की चुनाव सेना तैयार करेगी।

हाल ही किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लखनऊ और मद्रास ही ऐसे महानगर हैं, जहां के करीब ११ प्रतिशत निवासी मधुमेह के रोगी हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर (९.४ प्रतिशत) आता है। मधुमेह के सबसे कम रोगी चंडीगढ़ (१.५३ प्रतिशत) में हैं। पूरे देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या एक करोड़ बावन लाख आंकी गयी है।

एक अध्ययन के अनुसार मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सन २०२० तक पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म माननेवालों की संख्या २३ फीसदी हो जायेगी।

दिल्ली प्रशासन एक नयी नजीर कायम कर रहा है। उसने दिल्ली की झुग्गियों में रहनेवाले हर परिवार को एक धूम्ररहित चूल्हा मुफ्त देने का निश्चय किया है। दिल्ली प्रशासन का दावा है कि इससे ईंधन की खपत में ७५ प्रतिशत की बचत होगी और धुएं से होनेवाले प्रदूषण की भी रोकथाम हो जायेगी।

तीस जनवरी तक भारतीय खाद्य निगम ने ५२.९ लाख टन चावल की खरीद कर ली थी, जबकि गत वर्ष चावल की कुल खरीद ६८.९ लाख टन ही हो पायी थी।

भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख लोग कैंसर से मरते हैं।

प्रयाग के संगम क्षेत्र में चल रहे महाकुंभ मेले में महामंडलेश्वर गणेशानंद (हरिद्वार) के शिविर में ३५ वर्षीया एक महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ है। संदेह है कि युवती की हत्या १०-१५ दिन पूर्व कर दी गयी थी। महामंडलेश्वर पहले ही हरिद्वार चले गये थे और शिविर के अन्य लोग वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। किसी महाकुंभ या अर्धकुंभ में किसी धर्मगुरु के शिविर से किसी महिला का शव मिलने की यह पहली घटना है।

अंतरराष्ट्रीय आबादी केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सन २०२० तक पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म माननेवालों की संख्या २३ फीसदी हो जायेगी। इस समय कुल मुसलमानों की संख्या ९८ करोड़ है। यदि आबादी बढ़ने की यहीं रफ्तार रही, तो सन २०२० तक मुसलमानों की संख्या एक अरब, ९० करोड़ हो जायेगी और दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान होगा।

गुंजरात सरकार ने १९८९-९० के बजट में व्यवसाय कर सौ प्रतिशत बढ़ा देने के बावजूद २४८ करोड़ १० लाख रुपए का घाटा दिखाया है।

भारत के मानचित्र पर नौ राज्यों से होकर गुजरनेवाली पांच और सडकों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इनकी लंबाई १४७४ किलोमीटर है। नये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं—(१) पठानकोट से मंडी (२२० किमी), (२) ब्यावर-सिरोह-कांडला (४५० किमी), (३) निजामाबाद-जगदलपुर (४६० किमी), (४) मनोहरपुर से दौसा (राजमार्ग-८ की संपर्क सड़क ६४ किमी), (५) कोचीन से मदुरै (२८० किमी)। इन नये मार्गों को मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई ३३१६१२ किलोमीटर हो गयी है।

—संयोजन : विनोद मिश्र

लड़के लड़कियां कितना करीब आयें?

◆

स्वस्थ दोस्ती के लिए हजार जगहें होती हैं, क्लास रूम, लाइब्रेरी, हाल, कैंटीन, लान, गलियारे, सड़कें और पार्क। जिसे इन सब स्थलों पर एक दूसरे को जानने के बाद भी और ज्यादा जानने की जिज्ञासा शेष रहे, वह दोस्त अपने आप मुहब्बत की पहल कर सकता है।

◆

—ममता कालिया

दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में कुछ साल पहले तक लड़कों के बीच यह नारा प्रसिद्ध था कि अगर प्रेमिका की तलाश है, तो मिरांडा जाओ, पत्नी की तलाश है, तो इंद्रप्रस्थ जाओ और अगर बहन की तलाश है, तो लेडी श्रीराम जाओ। मिरांडा कालेज की लड़कियां अपने लिबास, हेयर स्टाइल, उच्चारण और उन्मुक्त अन्दाज में अलग पहचान ली जाती थीं। उनके आधुनिक मजाक प्राय: अन्य लड़कियों को समझ तक नहीं आते थे। साधारण किस्म के लड़के उनके सामने पड़ने से घबराते थे। इसी तरह सेंट स्टीफेंस के लड़के भी कुछ विलक्षण थे और उनकी स्मार्टनेस देखकर लड़कियां सोचा करती थीं, काश स्टीफेंस में उन्हें भी दाखिला मिल सकता। उस वक्त स्टीफेंस में केवल लड़के पढ़ते थे और मिरांडा में लड़कियां, फिर भी ये दो कालेज चर्चा के केंद्र में होते। अन्य कालेज सहशिक्षा केन्द्र होते हुए भी एक शांत गुमनाम अस्तित्व बनाये रहते। अगर कोई प्रेम-प्रसंग आग पकड़ लेता, तो यह माना जाता कि इसमें जरूर उन्हीं दो कालेजों के विद्यार्थी होंगे मानो दूसरे कालेजों में विद्यार्थी नहीं, पादरी पढ़ते हों।

वक्त अब बदल चुका है। स्टीफेंस के साथ-साथ मुल्क में और भी छोटी-बड़ी संस्थाओं में सहशिक्षा आरंभ हो गयी है। पहले वाले प्रतिबन्ध हट रहे हैं। लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हैं और उन्हें एक दूसरे का संपर्क हौवा नहीं लगता।

अब अगर इसके आगे जाने की प्रक्रिया में छात्र-छात्राएं मांग करें कि उनके होस्टल भी एक हों, कि कमरे में लड़के-लड़कियां इकट्ठे रहने को स्वतंत्र हों, कि संबंधों का औचित्य और अनुशासन वे स्वयं तय करेंगे, तो यह कहां तक मान्य होगा, कहना मुश्किल है। आजकल इंग्लैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज के विभिन्न कालेज छात्रों की इस मांग से बौखलाये हुये हैं। उन्होंने छात्रों के बीच मतदान कराकर देखा, अधिसंख्य छात्रों ने इस सह अस्तित्व के पक्ष में मत दिया। ट्रिनिटी क्लैर और किंग्ज कालेज ने अपने-अपने तरीके से मिक्स्ड होस्टल रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन क्वींस कालेज के डीन इस शुरुआत के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चे उन कालेजों में कतई न भेजें, जहां लड़के-लड़कियां एक ही कमरे में रहने को आजाद हों। डीन का विरोध हो रहा है। सहजीवन के समर्थकों का कहना है कि जब क्वींस कालेज शनिवार की शाम लड़के-लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाता, तो सोमवार को उन पर रोक लगाने की क्यों सोचता है? देखना यह है, कौन जीतता है?

अच्छा तो यह हो कि छात्र इस मामले में बड़ों की बात मानें। स्वस्थ दोस्ती के लिए हजार जगहें होती हैं, क्लास रूम, लाइब्रेरी, हाल, कैंटीन, लान, गलियारे, सड़कें और पार्क। जिसे इन सब स्थलों पर एक दूसरे को जानने के बाद भी और ज्यादा जानने की जिज्ञासा शेष रहे, वह दोस्त अपने आप मुहब्बत की पहल कर सकता है। विद्यार्थी जीवन संबंधों का मायालोक निर्मित करने का समय है, मायालोक तोड़ने का नहीं। इससे अधिक नजदीकी अध्ययन में बाधा पहुंचा सकती है और यह आगामी जीवन के प्रति एक निरुत्सुक दृष्टिकोण का सूत्रपात कर सकती है। अठारह साल के लड़के या लड़की के सामने जीवन अपनी सौ-सौ संभावनाओं के साथ प्रशस्त होता है, उसके पास असीम ऊर्जा, अदम्य उत्साह, अटूट आस्था होती है। वह वैज्ञानिक, चिकित्सक, कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ, दार्शनिक कुछ भी बन सकता है। इतने बहुरंगी, बहुआयामी व्यक्तित्व को महज सहजीवन की टेक पकड़कर सीमित करना अपने भविष्य को दंडित करना है। कहीं ऐसा न हो कि जितनी शक्ति इस सुविधा को प्राप्त करने में लगायी जाये, उससे ज्यादा शक्ति इस सुविधा से छुटकारा पाने में लगानी पड़े। क्या पता साथी लड़की को लड़के के खर्राटे, सोई मुद्रा, मोजों की बू, तम्बाकू भरी सांस और न जाने क्या-क्या नागवार गुजरे और वह दोस्त की जगह दुश्मन बन जाये? लड़की में ऐसी ही छोटी-छोटी बातें लड़के को बुरी लग सकती हैं।

हमारे यहां अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं उठी है। पर हर विदेशी हड़कम्प देर-सबेर हम तक पहुंच कर अपना प्रभाव डालता है। युवा वर्ग में अजनबीपन, आक्रोश, आत्मनिर्वासन, नाराजी, कुंठा-संत्रास के दौर इसी तरह के सागर पार आन्दोलनों के अक्स थे। अध्ययनकाल में सहजीवन की मांग हमारी सामाजिक संरचना के विरुद्ध हो जायेगी। बराबरी की सारी कागजी कार्यवाही के बावजूद हमारे यहां संबंधों की शतरंज में वह पुरुष के हाथ होती है। वही तय करता है कि स्त्री को कितने प्रतिशत आधुनिक होना है और कितने प्रतिशत पारम्परिक। औसत हिन्दुस्तानी मर्द स्त्री की आजाद-खयाली को एक व्यर्थ का चोचला मानता है। वह यह कतई पसंद नहीं करता कि लड़कियां शादी से पहले लड़कों से मित्रता रखें। कस्बों के कालेजों में सहशिक्षा का मतलब अकसर यह होता है कि अलग इमारत के अभाव में लड़के-लड़कियां एक ही इमारत में पढ़ें। कालेज में लड़के मुख्य फाटक के अन्दर प्रवेश करते हैं, लड़कियां पिछवाड़े के छोटे फाटक से सीढ़ियों के रास्ते सीधी ऊपर की मंजिल पर चली जाती हैं। उनका कामन रूम, गेम्ज रूम, सब अलग होता है। अगर कालेज में शिक्षक कम हुए, तो लड़के-लड़कियों की संयुक्त कक्षा रखी जाती है, अन्यथा उन्हें अलग-अलग क्लास में बिठाया जाता है। लड़के-लड़कियों की विशिष्ट उपलब्धियों का पता लगने पर ही उनमें एक दूसरे के प्रति चेतना पैदा होती है। कोई लड़का खेल में चमक जाता है, कोई पढ़ाई में, किसी को गाने में इनाम मिलता है, तो कोई चुनाव जीत जाता है। इस तरह उसके व्यक्तित्व की पहचान बनती है और वह लड़कियों के बीच एक नायक छवि अख्तियार कर लेता है। लड़की किसी क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करके कालेज में नाम-प्रतिष्ठा भले कमा ले, उसे फिर भी भय रहता है कि कहीं उसके चालचलन को लेकर सच्चा-झूठा किसी भी किस्म का अंपवाद न फैल जाये, जिससे उसका अब तक का अर्जित सारा यश चौपट हो जाये। लड़की के संदर्भ में उन्मुक्ता का अर्थ उच्छृंखलता माना जाता है और लोकप्रियता का अर्थ बदनामी। यहां शादी के ज्यादा काबिल वही लड़की समझी जाती है जो अन्दर से सीधी-सादी और ऊपर से थोड़ी बहुत स्मार्ट हो, जिसने स्वप्न में भी कभी किसी लड़के का सान्निध्य प्राप्त न किया हो और जो शरीर-संपर्क तो क्या शरीर-रचना तक के बारे में जानकारी के स्तर पर एकदम कोरी हो। एक अच्छी लड़की की अभिव्यंजना में कच्ची मटकी, कोरा कागज और सूधी गैया जैसे अलंकार प्रयोग किये जाते हैं। जहां तक ये बातें लड़की की गरिमा सुरक्षित रखने में कारगर हैं, वहां तक ये सही और सुन्दर हैं, लेकिन जहां इनसे मर्द की मुखियागिरी की बू आती है, वहां इन पर नये सवाल उठाये जा सकते हैं।

◆

तेज़ रफ़्तार से ऐसे कितने ही गड्ढों को
बिना तकलीफ़ पार कीजिए!

विक्रांत
एक भरोसेमंद टायर

जो उसी तकनोलॉजी से बना है जिसने
भारत के सर्वप्रथम ट्रक रेडियल टायर बनाए!

MAA COMMUNICATIONS VTL 388A HIN

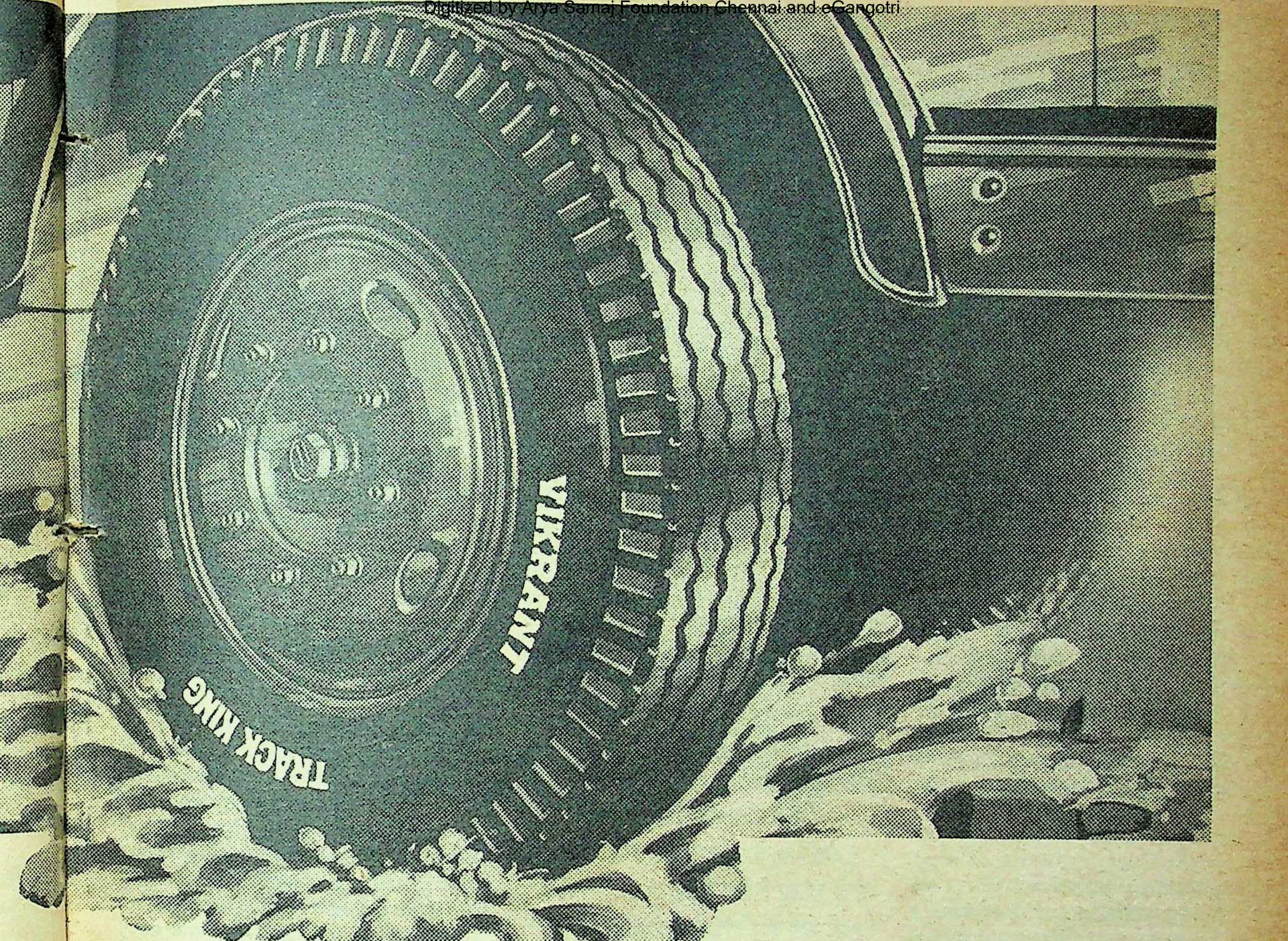

भारी वर्षा, आकस्मिक बाढ़, मीलों तक ज़गह जगह गड्ढे ..... भारत की सड़कों पर ऐसी परिस्थितियाँ एक आम बात हैं । एक टायर विशेष रूप से ऐसी ही चुनौतियों का हज़ारों मील तक मनों भार के साथ सामना करने के लिए बनाया गया है । और वह है विक्रांत — एक भरोसेमन्द टायर जिसे बनाने वाली आधुनिक तकनोलॉजी का उपयोग भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

विश्व की सर्वोत्तम ' रेसिंग टायर तकनोलॉजी '

हर विक्रांत टायर को बनाने में ब्रिटेन की ' एवॉन ' कम्पनी की तकनीकी उत्तमता का हाथ है । रेसिंग टायरों में प्रथम स्थान प्राप्त ' एवॉन ' से ही वाहनों के सरताज — रोल्स रॉएस — अपनी अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं । विक्रांत का ' अनुसंधान और विकास ' विभाग इसी ''एवॉन'' तकनोलॉजी में आवश्यक सुधार कर इसे भारतीय सड़कों के अनुरूप ढालता है ।

वही तकनोलॉजी जिसने भारत के सर्वप्रथम ट्रक 'रेडियल' टायर बनाए

जब विक्रांत के ' अनुसंधान और विकास ' विभाग ने अपना ध्यान ट्रकों के लिए रेडियल टायर बनाने पर केन्द्रित किया तो उसका परिणाम था एक ऐसा शक्तिशाली टायर जिसने फ़ौरन अपना स्थान ब्रिटिश बाज़ार में बना लिया। और इस तरह विक्रांत ट्रकों के लिए 'रेडियल' टायर बनाने व उसे ब्रिटेन निर्यात् करने वाली भारत की सर्वप्रथम कम्पनी बनी।

विक्रांत — उच्च श्रेणी के वाहनों का मूल उपकरण

विक्रांत ने अपने काम द्वारा सम्पूर्ण परिवहन उद्योग में अपनी विश्वसनीयता को साबित कर दिया है । इसीलिए यह ' टैल्को ' और ' अशोक लेलैण्ड ' जैसी उच्च श्रेणी की कम्पनियों द्वारा निर्मित वाहनों के लिए मूल उपकरण के रूप में चुना जाता है । साथ ही यह अधिकतम राज्य परिवहन निगमों की बसों में रोज़ हज़ारों लोगों को देश भर में जगह जगह ले जाता है ।

अतः अगर आप आधुनिक तकनोलॉजी से बना एक ऐसा टायर चाहते हैं जो अपने को साबित कर चुका हो और जिसपर आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भरोसा कर सकें तो स्पष्ट है आप सिर्फ़ विक्रांत को ही चुनेंगे ।

VIKRANT

भरोसेमंद टायर
ज़िम्मेदार कम्पनी

फांसी पर ऐसे लटकाये जाते हैं लोग

सरकारी आंकड़ों को सही मानें तो भी, पिछले साल पंजाब में आतंकवादियों ने २००० से अधिक लोगों की हत्या की है, अर्थात रोज करीब छह लोगों की। राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय और पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल चाहे जो भी दावा करें, किंतु इस दौरान आतंकवादियों ने अपनी मरजी से अपने शिकार चुने हैं और उन्हें कहां और कब मारना है, इसका फैसला भी स्वयं किया है। अब वे यह भी जता रहे हैं कि लोगों को मारने का तरीका चुनने में भी वे पूरा 'आजाद' हैं। एके-४७ या कारबाइन से निकलनेवाली बुलेटों की बौछार कुछ सेकेंडों में ही अनेक लोगों का काम तमाम कर सकती हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने 'शिकारों' को फांसी देने का जो तरीका अपनाया है, उसमें उन्हें अधिक समय की ज़रूरत होती है तथा खुद के पहचाने जाने और पकड़े जाने का खतरा भी होता है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्यावाले मामले में सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दी जाने के बाद से उन्होंने यह तरीका चुना है। जाहिर है कि कुछ इलाकों में आतंकवादियों की अदालतें बेरोकटोक लगती हैं और लोग उनसे खौफ खाते हैं। इन क्षेत्रों में आतंकवादी आराम से घूम-फिर सकते हैं और बिना किसी डर-भय के अपना काम कर सकते हैं।

विवेक शर्मा उन कुछ गांवों से होकर आये हैं जहां आतंकवादियों ने लोगों को फांसी दी है। प्रस्तुत है, उनकी रिपोर्ट:

आतंकवाद के शिकार: सरपंच रामपाल

◆

ग्रामीण नौजवानों के लिए आतंकवादी ही आदर्श बन गये हैं। उन्हें लगता है कि हथियार उठानेवालों के बड़े मजे हैं। उन्हें पैसा दिया जाता है और अमीर लोग अपने फार्म हाउस में उन्हें शरण देते हैं।

◆

बटाला-जालंधर राजमार्ग पर ही ५०-६० घरोंवाला भुजियांवाला गांव है। राजमार्ग से उतर कर ऊबड़-खाबड़ लिंक रोड पर बढ़ते ही चारों ओर हरे-भरे खेत मिलते हैं। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे गिल्ली-डंडा खेल रहे हैं, मवेशी आराम से हरी घास कुतर रहे हैं। इन सबसे एकदम शांति का आभास हो रहा है। लोग हमें आशंकित नजरों से देखते हैं और पुलिस के लोगों को देखने के बाद उनके चेहरे का डर छुपा नहीं रह पाता।

गांव में जाने पर पीपल का एक विशाल पेड़ दिखता है जो इर्द-गिर्द के घरों से कोई ५० गज दूरी पर होगा। ११ जनवरी की रात को इसी पीपल पर भुजियांवाला के चार ग्रामीणों को फांसी दी गयी थी।

स्तब्धकारी दृश्य : गांव में जो पांच-छह हिंदू परिवार हैं, वे सभी सरपंच रामपाल और उनके चचेरे भाइयों के हैं। ये सभी एक ही दादा से पैदा हुए हैं। उनके घर पास-पास बने हुए हैं। उस रात जब आधी रात को सरपंच के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और बताया कि वे लोग सीमा सुरक्षा बल की गश्ती टुकड़ी के हैं और रूटीन चेक के लिए आये हैं। जल्दी से दरवाजा खुला, तो सामने चार आतंकवादी खड़े थे जो केसरिया पटका पहने और लोई ओढ़े हुए थे। राइफलें उनके पास न थीं। वे जबरन घर में घुसे और सभी मर्दों से बाहर निकल जाने को कहा। उन्होंने दरवाजा खोलनेवाले रामपाल के हाथ बांध दिये। उनकी पत्नी ने फर्श पर लेटते हुए आतंकवादियों से दया की भीख मांगी। इस बीच आतंकवादियों का दूसरा गिरोह सरपंच के भाई सतपाल और उनके दो भतीजों तरसेम पाल और धरमपाल को ले आया। सरपंच के जिंदा बच गये एक भतीजे प्रेमपाल, जो पास ही के घर में रहते हैं, का अनुमान है कि आतंकवादियों की संख्या १५ होगी। प्रेमपाल दरवाजे पर दो बोरी अनाज लगाकर पीछे के एक कमरे में जा छुपा, इसी से उसकी जान बच गयी।

इसी बीच आतंकवादियों ने उन सभी लोगों के हाथ बांध दिये, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें बाहर ले गये। दरवाजे पर बाहर से कुंडियां लगा दी गयीं और घरवालों को कह दिया गया कि कोई रोने-धोने या शोर मचाने की हरकत न करे, वरना सब लोगों को उड़ा दिया जायेगा। प्रेमपाल इस डर से पास के खेतों में भाग गया कि आतंकवादी कहीं फिर न आयें। जब तीन-चार घंटे वे लोग नहीं आये, तो प्रेमपाल ने गांववालों को जगाया और वे लोग उन्हें ढूंढ़ने निकले। उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। सर्दी की धुंधली भोर में उन्हें पीपल की डाल से लटकते हुए उनके शव दिख गये। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था यह ! सरपंच और उनके भाई का शव एक ही रस्सी के दो छोरों पर बंधा था और अन्य दो दूसरी रस्सी से लटके थे। गांववाले याद करते हैं, तो आज भी स्तब्ध हो जाते हैं। रोती-बिलखती, हिचकियां भरती औरतें बताती हैं, "हम रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े—"सानू मार देयो, पर साडे आदियां न छड़ देयो।" आतंकवादियों ने परिवार वालों को भरोसा दिलाया, "हम इन्हें मारने नहीं ले जा रहे हैं। अगर हम चाहते तो मार ही देते। हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, सुबह तक इन लोगों को वापस भेज दिया जायेगा।"

इस घटना से सन्ना के गलियारों और लोगों के बीच आतंक की लहर दौड़ गयी। अगले तीन हफ्तों तक अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जिलों के कुछ गांवों में फांसी देने का क्रम जारी रहा जिसमें बारह लोग फांसी चढ़े।

दोहरा आतंकवाद : भुजियांवाला गांव के इन परिवारों में इस हादसे से काफी डर है और वे सदमे की हालत में हैं। इस हादसे से चार औरतें विधवा हो गयीं और १३ बच्चे अनाथ। औरतें निरक्षर हैं और सरकार ने उन्हें नौकरी देने का भरोसा दिया है। पर उनके घाव को भरने में अभी काफी वक्त लगेगा। सिसकती हुई सरपंच की विधवा, जिसे पांच बच्चों का पालन-पोषण करना है, कहती है, "साडी तो कमर ही टूट गयी।"

आतंकवाद के इस नये दौर से लोगों और पुलिस, दोनों का ही मनोबल गिरा है। घटनावाली जगह पर भिंडरांवाले टाइगर्स फोर्स आफ खालिस्तान का एक परचा मिला जिसमें इस घटना की जिम्मेदारी ली गयी थी और कहा गया था कि ऐसा सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी देने का बदला लेने के लिए किया गया है। सिर्फ जनवरी में ही १६० लोग आतंकवादियों के हाथ मारे गये। आतंकवादी गिरोहों में जिस हिसाब से नयी भरती हुई है, उससे लगता है कि पुलिस का यह अनुमान झूठा पड़ गया है कि आतंकवादी शक्तिहीन हो रहे हैं। इसके विपरीत आतंकवादी अपनी संख्या और हथियार बल बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। पुलिस का

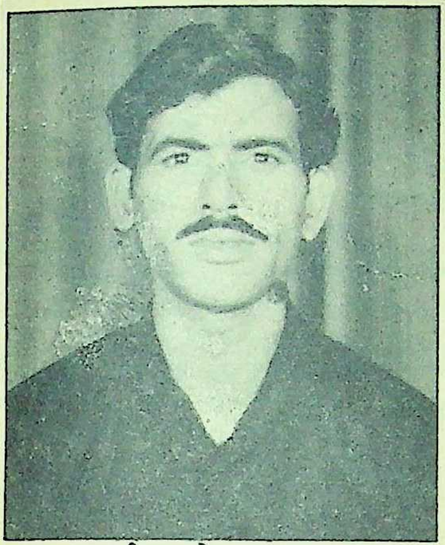

सतपाल का भतीजा तरसेम पाल

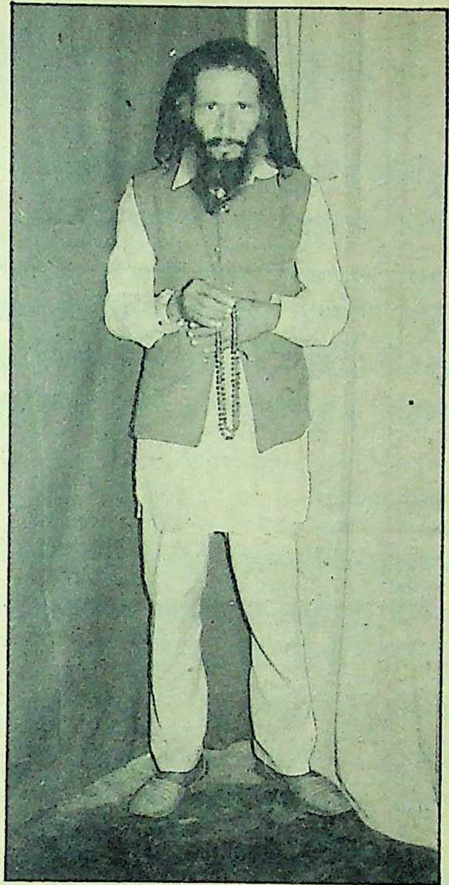

रामपाल का भाई सतपाल

सतपाल का भतीजा धरम पाल

दावा है कि उसने भी रोज चार या पांच आतंकवादियों का सफाया किया है, लेकिन आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी नहीं दिखती। इसलिए यही लगता है कि या तो नये दाखिल आतंकवादी भी उतनी ही सक्रियता दिखाने लगे हैं या पुलिस असली आतंकवादियों को मार ही नहीं पाती।

आतंकवाद की ओर लोगों को प्रेरित करने के लिए शक्ति और पैसा ही मुख्य आकर्षण लगते हैं। एक बैंक अधिकारी ने कहा, "अगर सिर्फ हथियार उठाने से कोई लड़का पैसा कमाने लगे, तो क्यों न हथियार उठायें? वे बेरोजगार भी हैं और कुंठित होकर आतंकवाद अपना रहे हैं।" ग्रामीण इलाकों के लोगों को आतंकवादियों और पुलिस दोनों के ही दमन का सामना करना पड़ता है। थोड़ा भी शक होने पर पुलिस पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को थाने बुला लेती है। अकसर हाजत में क्षमता से अधिक लोग होते हैं और पेशाब-पाखाने की भी सुविधा नहीं होती। जानकारियां उगलवाने के लिए कई बार उनकी पिटाई भी होती है जिससे निर्दोष लोगों में भी जलील होने का मलाल भर आता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "गांववाले पुलिस पर भी भरोसा नहीं करते। आतंकवादियों का डर उनके मन में गहरा समा गया है।" दूसरी ओर ग्रामीण नौजवानों के लिए आतंकवादी ही आदर्श बन गये हैं। उन्हें लगता है कि हथियार उठानेवालों के बड़े मजे हैं। उन्हें पैसा दिया जाता है और अमीर लोग अपने फार्म हाउस में उन्हें शरण देते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन किसानों की बेटियों के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। फिर भी वे बदले के डर से पुलिस को खबर नहीं देते।

बटाला जिले के कुछ गांवों का दौरा करने के बाद यह पाया गया कि कुछ गांवों में तो अब एक भी हिंदू परिवार नहीं रह गया है। अधिकांश हिंदू गांव छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अपना घर-बार छोड़ गये इन लोगों में से अधिसंख्य लौटेंगे ही, क्योंकि शहरों में उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता।

> बेकारी हटा दीजिए, सारी समस्याएं सुलझ जायेंगी। जितना पैसा सुरक्षा पर खर्च होता है उतना अगर रोजगार देने पर हो, तो आतंकवाद का खेमा उखड़ जायेगा। लड़कों को काम मिलने के साथ ही वे हथियार छोड़ देंगे।

पुलिस बल विफल: पुलिस में भ्रष्टाचार के बारे में भी काफी कुछ कहा जा रहा है। अमृतसर की एक कंपनी के अधिकारी कहते हैं, "पंजाब में दो तरह का आतंकवाद है—एक तो आतंकवादियों का और दूसरा सरकार का।" अधिकारी कहते हैं कि अकसर उन्हें सचाई जानने के लिए कड़ाई पर उतरना पड़ता है और कभी-कभार इसका शिकार निर्दोष लोग भी बन जाते हैं।

जब तक जनता के लोग मौजूदा माहौल के खिलाफ नहीं उठ खड़े होते, तब तक आतंकवाद मिटाने की दिशा में खास कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ ऐसे लोग ही आतंकवादियों के ठिकानों के बारे में पुलिस को पक्का सुराग दे सकते हैं। पुलिस अपने दम पर ही इस बला से नहीं निपट सकती। दुखद आश्चर्य इस बात का है कि इस तथ्य को जानते हुए पुलिस जन-सहयोग पाने में विफल है।

शाम होते ही पूरे पंजाब में कर्फ्यू लग जाता है। सारी गतिविधियां थम जाती हैं। भुजियांवाला गांव के एक किसान का कहना है, "रात में हम पेशाब करने भी घर से बाहर नहीं निकलते।" अमृतसर की मुख्य मंडी हाल बाजार में पहले देर रात तक चहल-पहल रहती थी, पर अब शाम साढ़े छह बजे के बाद ही वह सुनसान हो जाती है।

अमावस्या की सुबह सात बजे तक स्वर्णमंदिर के हरमंदिर साहिब में सिर्फ ३६ लोग थे। एक समय था जब इस अवसर पर भीड़ लगी रहती थी। १० बजे रात के बाद इस शहर में एकदम खामोशी छा जाती है। पुलिस वाले भी देर रात को नहीं दिखते। क्या सिर्फ ठंड के कारण ही ऐसा होता है?

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी के एक सदस्य कहते हैं, "कमेटी के चुनाव कराके ही पंजाब समस्या को सुलझाया जा सकता है।" इसी प्रकार अकाली और इंकाई यह कहते हैं कि उनकी पार्टियों की सरकार बनने से ही समस्या सुलझेगी। लेकिन असली जवाब देता है निरक्षर किसान दीदार सिंह, "बेकारी हटा दीजिये, सारी समस्याएं सुलझ जायेंगी। जितना पैसा सुरक्षा पर खर्च होता है उतना अगर रोजगार देने पर हो, तो आतंकवाद का खेमा उखड़ जायेगा। लड़कों को काम मिलने के साथ ही वे हथियार छोड़ देंगे।"

फिर नेता अपनी उपलब्धियां गिनाने की जगह तर्क संगत ढंग से क्यों नहीं सोचते? दीदार सिंह कहता है, "अगर इस हकीकत को मंजूर कर कदम बढ़ाया गया होता, तो शायद पंजाब समस्या ही न पैदा होती।" किंतु आज पंजाब का भविष्य भी अधर में लटका है, ठीक पीपल के पेड़ से लटके चार शवों की तरह। ■

मनोरमा

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

गृहशिल्प तथा हस्तशिल्प से सम्बन्धित विषयों पर आधारित एक संग्रहणीय अंक।

कढ़ाई, क्रोशिया तथा सिलाई विशेषांक एक ऐसा अंक जिसमें हर आयु की महिलाओं की पसंद. के अनुरूप उपयोगी तथा दिलचस्प रचनायें दी जा रही हैं।

विशेष आकर्षण :

- स्मॉकिंग से सजाइये बिटिया का फ्राक
- कढ़ी हुई जैकटें नवयुवतियों के लिये
- क्रोशिये से की गई सजावट
- कढ़ी हुई साड़ियां
- मैट्स, सेन्टरपीस, मेजपोश, पलंगपोश तथा शापिंग बैग और स्लीपर के नये निराले नमूने

आवरण कथा

यदि आपके पति आपके बॉस हों

एक रोचक विश्लेषण

साथ ही

मेरी सुहागरात, चक्रव्यूह, फैशन, व्यंजन, फुरसतनामा तथा कहानियां सहित सभी स्थाई स्तंभ हमेशा की तरह

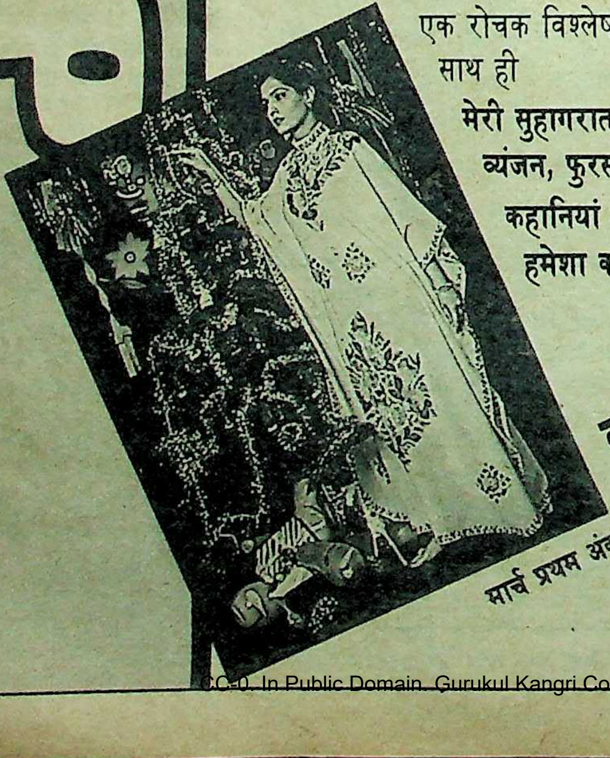

मार्च प्रथम अंक

कढ़ाई, क्रोशिया व सिलाई विशेषांक

दो दुश्मनों के बीच जनता दल

महाराष्ट्र में कांग्रेस-इ और शिवसेना जैसी दो जबर्दस्त ताकतों के प्रतिद्वंद्वी की शक्ल में उभरे जनता दल की राजनीतिक संभावनाएं क्या हैं?

महाराष्ट्र में दो ही राजनीतिक ताकतें हैं, एक कांग्रेस-इ और दूसरी शिवसेना। राजनीतिक गतिविधि से जुड़नेवाले हर व्यक्ति, समूह अथवा संगठन को दोनों में से किसी एक का सहारा लेना होता है। कहते हैं, राजनीतिक जेहनवाले इन संगठनों को ये ताकतें लील जाती हैं। दोनों के बीच आनेवाले पिस जाते हैं और दोनों से दूरी रखनेवाले गायब हो जाते हैं। इसीलिए जनमोर्चा, कांग्रेस-स, लोकदल-ब आदि दलों का यहां कोई वजूद नहीं बन पाया। इस परंपरा को चुनौती देते हुए जनता दल ने महाराष्ट्र में अपने पहले जलसे के साथ ही कांग्रेस-इ और शिवसेना, दोनों से मुकाबले की जुर्रत की है। मार्के की बात यह है कि दोनों ताकतें जनता दल को 'तीसरी ताकत' के रूप में देखती हैं, अपना प्रतिद्वंद्वी मानती हैं, मगर दोनों में से कोई उसकी हस्ती मिटाने में सक्षम नही दिखायी देतीं। शायद इसलिए कि दोनों जितनी एक दूसरी के खिलाफ हैं, उतनी जनता दल के खिलाफ नहीं हैं।

१९८८ की समाप्ति के एक दिन पूर्व, ३० दिसंबर को शिवसेना ने अपने राज्यस्तरीय पुणे अधिवेशन में भारी भीड़ जुटाकर और तड़क-भड़क दिखाकर अपनी जन-धन-शक्तिसंपन्नता को साबित कर दिया था। उस आडंबरपूर्ण जमावड़े में शिवसेना-प्रमुख बाल ठाकरे ने जहां अपनी दोहरी सामर्थ्य से सत्तारूढ़ दल को ललकारा, वहीं मुख्यमंत्री शरद पवार की तीखी आलोचना कर किसी तरह के समझौते की संभावना भी खतम कर दी। शिवसेना की इस चुनौती का जवाब (भले वह मुंहतोड़ न रहा हो) मुख्यमंत्री पवार ने १६ जनवरी को औरंगाबाद में इंकाई जमघट के दौरान दिया, जब पार्टी को शिवसेना के विरुद्ध हमलावर बनाने का फैसला किया गया।

मतभेदों में कमी: इन दो बड़े राजनीतिक जलसों के बाद गत २९ जनवरी को जनता दल ने पुणे में अपनी 'राज्य शाखा' का स्थापना अधिवेशन किया। इसे जनता दल का जमावड़ा भले ही कहा जाये, पर यह पूरी तरह पुरानी जनता पार्टी का ही जलसा था। इस जलसे को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब एक दिन पहले ही डा० दत्ता सामंत की कामगार आघाड़ी ने उसमें विलय से इनकार कर दिया। उधर विश्वनाथ प्रताप सिंह से सहानुभूति रखनेवाली शेतकरी-संघटना के नेताओं ने भी दूरी बनाये रखी। उनका कहना है कि संघटना किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होगी, न ही पार्टी के मंच पर जायेगी।

पुणे सम्मेलन में जनता दल ने यह बात साबित कर दी कि जितने लोग नये दल में आ चुके हैं, उनमें मतभेद घट रहे हैं। उपस्थिति तथा भाषण दोनों से यह बात साबित होती रही। चंद्रशेखर को छोड़कर सारे राष्ट्रीय नेता अधिवेशन में आये थे। महाराष्ट्र जनता दल के महासचिव डा० रत्नाकर महाजन ने चंद्रशेखर की गैरहाजिरी को लेकर लोगों की अटकलबाजी पर सफाई दी, "उन्होंने (चंद्रशेखर) पहले सूचित किया था कि वे नहीं पहुंच पायेंगे।" वे उत्तर प्रदेश में जयप्रकाशजी के नाम पर लगाये गये बड़े शिविर में व्यस्त थे। किंतु महाराष्ट्र में उनके अनुयायी समझे जानेवाले सारे लोग जलसे में हाजिर थे।

सामंत की शर्त: अधिवेशन में डा० दत्ता सामंत के मजदूर समर्थकों की गैरहाजिरी अलग खटक रही थी। खासकर इसलिए कि डा० दत्ता सामंत की दोस्ती से वीपी सिंह बंबई में भारी उम्मीदें लगाये हुए हैं। वे आये और मंच से भाषण देकर चल दिये। एक बड़े नेता ने 'माया' को बताया, "डा० सामंत की पहली शर्त थी कि उन्हें बंबई जनता दल का अध्यक्ष बनाया जाये। इस पद पर विराजमान रणजीत भानू ने काम भले कुछ न किया हो, लेकिन वे जार्ज फर्नांडीस के दाहिने हाथ हैं। भानू को निकालने पर पुरानी समाजवादी लाबी हंगामा खड़ा कर देती। इसलिए डा० सामंत को खुश करने की वीपी की हिम्मत नहीं पड़ी। यों २७ जनवरी को महाराष्ट्र जनता पार्टी के महासचिव डा० महाजन ने घोषणा की थी कि कामगार आगाड़ी के नेता अधिवेशन में रहेंगे। शाम को आघाड़ी का स्पष्टीकरण पहुंच गया। डा० महाजन ने 'माया' से कहा, "डा० सामंत जनता दल की राष्ट्रीय कार्यसमिति के आमंत्रित सदस्य हैं। इसलिए मैं तो यही मानकर चलूंगा कि वे हमारे साथ हैं। हो सकता है, विलय की रस्म-अदायगी में समय लगे।"

जनता दल के गठन के समय राज्य स्तरीय 'शेतकरी कामगार पक्ष' को भी विलय का न्यौता दिया गया था। कट्टर शिवसेना-विरोधी इस क्षेत्रीय पार्टी ने बाहर रहकर सहयोग करने का फैसला किया।

इन फैसलों की छाया पुणे अधिवेशन पर नजर आयी। जनमोर्चा के संस्थापक-संयोजक विधायक बाबू राव मापसे ने 'माया' से कहा, "यह सही है कि हमारे अधिवेशन में शिवसेना या कांग्रेस की तरह भीड़ नहीं थी, परंतु हमने किसी को आने के लिए न गाड़ी दी, न रकम। खास बात यह थी कि इस अधिवेशन में भारी संख्या में किसान शामिल हुए।"

भाषण की होड़: देहाती इलाकों से काफी लोग आये जरूर, किंतु यह भी सच है कि शिवसेना के अधिवेशन में नौजवानों की जो भीड़ नजर आयी, उससे यह कम थी। अधिवेशन में जो कुछ भीड़भाड़ थी, वह भी जनता दल के राष्ट्रीय 'युवा नेता' अभिनेता राज बब्बर के इर्द-गिर्द ही थी। उन्होंने भाजपा तथा कांग्रेस की तर्ज पर नारे लगाये—"देश का नेता कैसा हो, राज बब्बर जैसा हो।"

बड़े नेताओं के नाम का प्रचार करने के

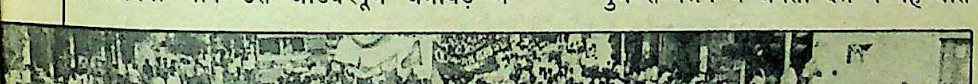

एक ही विकल्प: पुणे में दलित संगठनों के साथ जनता दल का जुलूस

इन-दिनों साप्ताहिक

क्या हो रहा है देश-विदेश और राज्यों में ?
इसका जबाब पढ़िये 'इन दिनों' साप्ताहिक में.

☐ राजनीतिक एवं अन्य समसामयिक घटनाओं की विश्वसनीय रिपोर्ट
☐ तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित ताजातरीन घटनाएं
☐ खोजपूर्ण एवं निष्पक्ष विश्लेषणात्मक लेखा-जोखा
☐ साथ में अनेकों स्थाई स्तम्भों कें अंतर्गत ढेरों रोचक सामग्री

इन-दिनों
राजशाही के ताने बाने बुन रहे हैं वी.पी.
तांत्रिक अनुष्ठान करा रहे हैं अर्जुन सिंह ?

भारत के साप्ताहिक समाचार
पत्रों में सर्वाधिक खोजी
एवं विश्वसनीय
'इन दिनों' साप्ताहिक !

हर पल की रखे खबर !

'इन दिनों' साप्ताहिक समाचार पत्र

'इन दिनों' की उपहार प्रतियोगिता योजना

इन दिनों के वार्षिक ग्राहक बनकर जीत सकते हैं आप
अनेकों आकर्षक पुरस्कार

▪ प्रथम वार्षिक ग्राहकों के लिए आकर्षक गारंटीशुदा पुरस्कार
▪ इन दिनों आपको कैसा लगा, विषय पर 'स्लोगन' (20 शब्दों में) भेजकर जीतिए आकर्षक पुरस्कार !

इसी के साथ भाग्यशाली वार्षिक ग्राहकों के लिए
एक लक्की ड्रॉ योजना – जिसमें आप जीतेंगे –

● प्रथम पुरस्कार : मारुति एयरकंडीशन-डीलक्स कार
● द्वितीय पुरस्कार : स्कूटर (2) प्रत्येक को एक
● तृतीय पुरस्कार : कलर टी०वी० (4) प्रत्येक को एक
● सांत्वना पुरस्कार : फ्रिज, टेपरिकार्डरस, घड़ियां, मिक्सी आदि

जल्दी कीजिये ! 100 रु. का मनीआर्डर भेजकर
वार्षिक ग्राहक बनिये

अन्तिम तिथि 30 अप्रैल

ऐजेन्टों के लिए
भी पुरस्कार योजना

इन दिनों (साप्ताहिक) 17, होटल कांटीनेंटल एनेक्सी, रीगल बिल्डिंग,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन : 310038

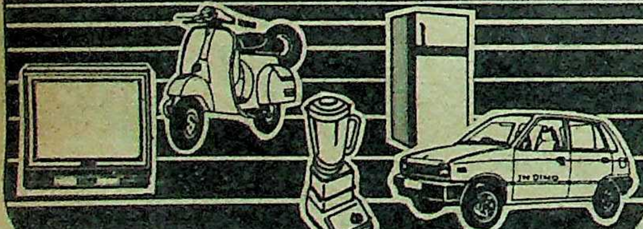

बावजूद जनता दल मराठों को आकर्षित करने में असफल रहा। महाराष्ट्र जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद संभाजी राव काकड़े खुद '९६ कुड़ी' के मराठा हैं, यानी शिवाजी, यशवंत राव चह्वाण अथवा शरद पवार से ज्यादा ऊंचे। पुणे उनका कार्यक्षेत्र है, फिर भी लाखों की भीड़ में मराठे कुछ हजार ही थे।

जैसा कि अनेक नेता मंजूर करते हैं, अल्प-संख्यको तथा दलितों ने अच्छे रुझान का परिचय दिया। धुले के आदिवासी क्षेत्र से सैकड़ों गोंड परिवार जद के जलसे में पहुंचे। पुणे पहुंचने के लिए अमरावती से आटोरिक्शों में २०-२० घंटे खडे रहकर लोगों ने सफर किया। आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे नक्सली प्रभावित क्षेत्र सिरोंचा तक के कार्यकर्ता पहुंचे। राष्ट्रीय संजय मंच के महाराष्ट्र के संयोजक रह चुके महेश पुरोहित ने इतना जरूर मंजूर किया कि अव्यवस्था के चलते यह कांग्रेसी सम्मेलन बनकर रह गया। हर बडा नेता एक कार्यक्रम में भाषण देता और दूसरे कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाता था। इस चक्कर में मंझोले नेता मारे गये। सभी कार्यक्रमों में पहुंचने की होड़ में गड़बड़ियां होती रहीं।

आसार और मुश्किलें : कुल मिलाकर जनता दल के हाथ क्या लगा ? क्या वह अपने वोट-बैंक को पहचानने में सफल हो सका ? क्या उसकी जड़ें जम सकेंगी, खासतौर पर तब अब जनता पार्टी के गढ़ कोंकण अंचल में वह छिन्न-भिन्न हो चुका है और जहां से एक हजार कार्यकर्ता भी नहीं आये ? मोटर-सायकिलों व ट्रकों के कारवां-जुलूस वोट खींच सकेंगे ?

वरिष्ठ विधायक मापसे का दावा है, "सबने वीपी सिंह को राजीव गांधी का विकल्प मान लिया है। बच्चा-बच्चा उन्हें जानने लगा है। इसलिए कांग्रेस से ऊबे-उकताये तथा शिवसेना को पसंद न करनेवाले मतदाता के सामने जनता दल ही विकल्प है।" लेकिन आम नागरिक में यह अधिवेशन खास आकर्षण पैदा नहीं कर सका। जनता दल के अंचल संयोजक महेश पुरोहित ने तो पास जाकर अध्यक्ष वीपी सिंह से अनुरोध भी किया, "नेताओं तथा भाषणों की भरमार के बजाय जनसंपर्क तथा संगठन बनाने पर जोर दिया जाये।" उन्होंने सिंह को तालुका स्तर तक दौरा करने की सलाह दी। बंबई में बारंबार दौरों के बावजूद पार्टी की हालत को देखते हुए वीपी सिंह को निश्चित ही इस बारे में सोचना पड़ेगा। भले ही बंबई में मृणाल गोरे जैसी नेता (जिन्हें जनता दल ने संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया है) हों, लेकिन दल का मजबूत आधार नहीं है। यहीं कारण है कि महाराष्ट्र में जनता दल अल्पसख्यकों, पिछड़ों तथा हरिजनों को संगठित करने में जुटा है। एक फरवरी को सभी दलित संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए जनता दल नेताओं ने विशाल जुलूस निकाला। समाज-सुधारक महात्मा फुले के बारे में पुणे की मराठी पत्रिका 'सोबत' ने अपमानजनक बातें छापी थीं। 'सोबत' के संपादक बेहटे कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। बाल ठाकरे ने बेहटे का बचाव करने की कोशिश की थी। इस तरह अब शिवसेना से टकराकर जनता दल बाकी वर्गों का विश्वास अर्जित करने का प्रयत्न करेगा। और यही होगी महाराष्ट्र की 'थर्ड फोर्स'। कांग्रेस का असंतुष्ट वर्ग जनता दल को परोक्ष समर्थन देगा।

फिर भी जनता दल का रास्ता आसान नहीं है। भले ही उसके कुछ नेताओं का सहकारी चीनी कारखानों में वर्चस्व हो या विधानसभा में उसके २२ विधायक हों। राज्य स्तर पर अंदरूनी फटमफाट काफी है। जनता में समाजवादी-गैरसमाजवादी गुट हैं। विलयपूर्व की घटकबाजी कायम है। विधायकों में अविश्वास है। शेतकरी संघटना के नेता कांग्रेस-स विधायक डा० वसंत बोंडे समेत कुछ लोग जनता दल में जाने को तैयार थे, परंतु सम्मानजनक तरीके से बुलावा नहीं पहुंचा।

वैसे जनता दल को मुख्यमंत्री शरद पवार तथा वीपी सिंह की दोस्ती को लेकर कई उम्मीदें हैं। आज तक श्री पवार ने वीपी की, व्यंक्तिगत आलोचना नहीं की। कहते हैं, दोनों के बीच 'अनुबंध-सेतु' है—जो गुल खिलायेगा।

—बंबई ब्यूरो

इस्पात नगरी में उठे हक के सवाल !

जमशेदपुर में नागरिक सुविधाओं के सवाल पर टाटा की जमींदारी के खिलाफ वातावरण क्यों बन रहा है? क्या सचमुच देश के चंद सुव्यवस्थित शहरों में एक जमशेदपुर अव्यवस्था का शिकार है?

"इस ओल्ड सोनारी बस्ती में जिनके घर कुंआ है, वे भाग्यवान और ऐश्वर्यशाली समझे जाते हैं। यह सोनारी बस्ती भी देश के सर्वाधिक स्वच्छ और सुव्यवस्थित कहे जानेवाले शहर जमशेदपुर का ही हिस्सा है, जहां आज तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। सोनारी बस्ती के जिन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक है, उन लोगों ने अपने-अपने घरों में कुएं खुदवा रखे हैं। गर्मी के दिनों में ये कुएं भी सूख जाते हैं। तब सोनारी के सभी लोगों को काफी दूरी तय करके 'टिस्को' के नल से पानी ढोकर लाना पड़ता है। पुरुष व बच्चे तो उस सार्वजनिक नल पर भी स्नान कर लेते हैं, पर घर की औरतों के लिए रोजाना की परेशानी है।" कहते-कहते सोनारी बस्ती के पुराने बाशिंदे वयोवृद्ध आरएम सिंह एकदम से उत्तेजित हो उठते हैं। सचमुच सोनारी बस्ती के लोग आज भी आदिम जीवन जी रहे हैं। सोनारी के ही एसके मोइत्र और टीके बेरा 'माया' से कातर स्वर में कहते हैं, "सिर्फ पानी ही नहीं, ड्रेनेज और सीवरेज का भी कोई इंतजाम यहां नहीं है। जानवरों से भी बदतर हालत में जीते हैं, हम सब। यह बस्ती टाटा की जमींदारी में है और इसलिए सामान्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी टाटा प्रबंधन द्वारा नियंत्रित 'नोटीफाइड एरिया कमेटी' के जिम्मे है। पर जब कभी नोटीफाइड एरिया के अधिकारियों से हमने अपनी परेशानियां बतायीं, तब एक ही उत्तर मिला कि इस इलाके की नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है। पर अगर एक गड्ढा भी हमें अपनी जरूरत के लिए खोदना पड़े, तो पहले नोटीफाइड एरिया कमेटी से इजाजत लेनी होती है। टाटा की जमींदारी और बिहार सरकार के बीच जमशेदपुर के लाखों लोग इस तरह तिल-तिल कर घुटते हुए जी रहे हैं।" बदहाली की यह स्थिति सिर्फ जमशेदपुर की सोनारी बस्ती के लोग ही नहीं भोग रहे हैं, बल्कि उलियान, प्रेम नगर, शास्त्री नगर और बिरसा नगर सरीखे इस शहर के ऐसे अनगिनत हिस्से हैं जो नारकीय जिंदगी जी रहे हैं। बिजली की आपूर्ति तो महज एक सपने की बात है।

नगर निगम के खिलाफ : लगभग १५, ७२५ एकड़ में बिहार सरकार ने भू-अर्जन एक्ट के तहत टाटा को जमींदारी दे रखी है। टाटा की जमींदारी के क्षेत्र में सामान्य नागरिक सुविधा सुलभ कराने के लिए जमशेदपुर में विधिवत निर्वाचित नगर निगम के बजाय एक नोटीफाइड एरिया कमेटी है। इसमें निर्वाचन की पद्धति के बजाय मनोनयन की व्यवस्था है और यह कमेटी पूरी तरह टाटा प्रबंधन के अधीन संचालित है। जमशेदपुर के अधिकांश लोग इस बात को लेकर सख्त नाराज चल रहे हैं कि नोटीफाइड कमेटी शहर के चुनिंदा हिस्सों में ही नागरिक सुविधा उपलब्ध कराती है और टाटा जमींदारी के क्षेत्र में पड़नेवाले बहुतेरे हिस्से उपेक्षित और बिलकुल नरक की सी हालत में हैं। लिहाजा, इधर कुछ महीनों से जमशेदपुर में नोटिफाइड एरिया कमेटी भंग कर टाटा-प्रबंधन की नगर व्यवस्था समाप्त करने की मांग ने जोर पकड़ रखा है। शहर के लोगों की बस एक मांग है कि आठ लाख की आबादीवाली इस इस्पातनगरी में एक अदद निर्वाचित नगर निगम की सरकार व्यवस्था करे। दूसरी तरफ टाटा-प्रबंधन किसी सूरत में नगर निगम की व्यवस्था को कबूलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। संघर्ष जारी है, सड़क से अदालत तक।

नगर निगम लेकर रहेंगे : दुलाल मुंशी

दुखद स्थिति : केदार महतो

इस संघर्ष को शहर में चलाकर टाटा की नगर व्यवस्था के विरुद्ध वातावरण तैयार करने के लिए जमशेदपुर के कुछ जागरूक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जहां 'जमशेदपुर नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति' नामक संगठन बनाया है, वहीं शहर के एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता जवाहर शर्मा ने नगर की कुव्यवस्था के सवाल पर टाटा प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला ठोंक रखा है। नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति जोर-शोर से इस मांग के प्रश्न पर सेमिनार व गोष्ठी आदि का आयोजन कर रही है। इस तरह यह मामला दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के संयोजक दुलाल मुंशी 'माया' से कहते हैं, "सुरक्षा समिति के गठन की पृष्ठभूमि भी अद्भुत है। हुआ यों कि जब जवाहर शर्मा ने नगर की बदहाली के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवेदन दिया, तो टाटा प्रबंधन ने इसका जवाब देने के लिए फौरन सिटीजंस फोरम नामक एक संस्था गठित करवायी और जमशेदपुर में नगर निगम की मांग का विरोध किया। टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा भी नगर निगम की मांग का विरोध कराया गया। इसलिए शहर के जागरूक लोगों को लगा कि हमें भी अपने संघर्ष को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक संगठन बनाना चाहिए और इस तरह नागरिक अधिकार सुरक्षा समिंति गठित हुई।

"जमशेदपुर शहर की स्थिति प्रशासनिक रूप से अत्यंत दुखद है। इस शहर को प्रशासनिक रूप से दो भागों में बांट रखा गया है—एक बिहार सरकार के जिम्मे, एक टाटा प्रबंधन के जिम्मे। बिहार सरकार के अधीन जुगसलाई, मानगो, आदित्यपुर और कुछ पंचायती इलाके हैं तथा टाटा जमींदारी के अधीन बिस्टूपुर, साकची, धनकीडीह, कदमी, सोनारी, टेल्को क्षेत्र, ट्यूब क्षेत्र, बारीडीह, प्रेमनगर आदि इलांके आते हैं। बिहार सरकार व टाटा प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर फेंक कर निश्चिंत हैं और शहर के लोग तबाह हैं। इसलिए अब यह बदहाली यहां के लोग झेलने को तैयार नहीं हैं। नगर निगम की मांग हम पूरी करवा कर दम लेंगे," जमशेदपुर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता केदार महतो 'माया' से कहते हैं, "एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार है, जमशेदपुर। पूरे देश में यही एक मात्र शहर है, जिसकी व्यवस्था सरकार नहीं एक औद्योगिक घराने के हाथ में है।"

अदालती लड़ाई : आखिर जमशेदपुर के लोग टाटा जमींदारी की व्यवस्था में किस तरह के भेदभाव की शिकायत करते हैं और टाटा प्रबंधन की इस बावत क्या सफाई है, इसे समझने के लिए शहर के लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाहर शर्मा द्वारा दायर याचिका और टाटा प्रबंधन का उस याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ जवाब देखना जरूरी है। जवाहर शर्मा ने अपनी याचिका (संख्या १५४/१९८८) भारतीय संविधान की धारा १४, २१, ४८ और ५१-ए के तहत दायर की। अपनी याचिका में जवाहर शर्मा ने कहा है कि वे जमशेदपुर के आठ लाख निवासियों की ओर से यह याचिका दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकील रानी जेठमलानी हैं। जवाहर शर्मा ने याचिका में कहा है कि बिहार सरकार की गलत नीति के कारण टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी

सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष: जवाहर शर्मा

जुगसलाई भी समस्या-ग्रस्त: रतन जोशी

(टिस्को) जमशेदपुर के आमलोगों के अधिकारों से खेल रही है। १९०७ के बाद से जमशेदपुर और इसके समीपवर्ती कुछ इलाकों पर टाटा प्रबंधन का आधिपत्य शुरू हुआ। यह जमीन, जिस पर टाटा की जमींदारी है, तत्कालीन ढालभूम स्टेट के राजा से औद्योगिक कांपलेक्स के विकास तथा अन्य सामाजिक उद्देश्यों, मसलन अस्पताल, पार्क और स्कूल आदि के निर्माण के नाम पर निहायत मामूली कीमत पर खरीदी गयी थी। यद्यपि औद्योगिक कांपलेक्स की स्थापना यहां की गयी जो कंपनी के अपने हित की बात थी, पर यहां के स्थानीय निवासियों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। याचिका में आगे कहा गया है कि टाटा प्रबंधन के मनमाने कार्यों पर रोक लगाने के लिए बिहार विधान मंडल ने १९७२ में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया। पर इसी बीच टाटा प्रबंधन ने इसी अदालत से बिहार भूमि सुधार (संशोधन) कानून १९७२ के विरुद्ध स्थगन आदेश पाने में सफलता प्राप्त कर ली। इस तरह उक्त स्थगन आदेश के आधार पर इस क्षेत्र पर टाटा प्रबंधन की पकड़ और मजबूत हो गयी। फिर इसी दौरान टाटा प्रबंधन ने राज्य सरकार की सर्वे-सेटलमेंट के कारण पड़ी कुछ विवादास्पद जमीन को भी अपने कब्जे में ले लिया।

१९८४ में फिर टाटा प्रबंधन ने बिहार सरकार से 'लीज' पाने में सफलता हासिल कर ली। १९८४ में हुए लीज के प्रसंग में कहा गया कि कंपनी ने जमशेदपुर का विकास जारी कर रखा है। पानी, बिजली, सड़क व भवन निर्माण सरीखे सभी मामलों पर कंपनी तत्पर है। लेकिन जवाहर शर्मा ने याचिका में कहा है कि कंपनी द्वारा नागरिक सुविधा सुलभ कराने की यह बात सफेद झूठ है। याचिका के अनुसार वस्तुतः ये सुविधाएं चंद विशेषाधिकार संपन्न पदाधिकारियों और टाटा कर्मचारियों तक ही सीमित हैं, जिनकी अनुमानित संख्या दो लाख है। शहर के शेष सात-आठ लाख लोग अर्द्धमानवीय अवस्था में जी रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि जमशेदपुर को जिले का भी दर्जा मिल गया होता, लेकिन टाटा प्रबंधन के अड़ंगे के कारण यह आज तक संभव नहीं हो सका। नागरिक सुविधाओं के नाम पर यही एक नोटीफाइड एरिया कमेटी है, जिसके पदाधिकारियों को कंपनी द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस तरह यह नोटीफाइड कमेटी अस्तित्वहीन है। १९८४ के लीज समझौते की प्रस्तावना में कहा गया है कि समूचे जमशेदपुर शहर की नागरिक सुविधाओं के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी होगी। पर कंपनी इस जिम्मेदारी से अपने को मुक्त मानती है। बिहार सरकार के पास भी जब नगर के परेशान निवासियों ने समस्या रखी, तो सरकार उदासीन रही। जवाहर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि यह सचमुच एक विरोधाभास ही है कि एक संप्रभु राज्य अपनी जमीन का एक बड़ा भाग एक कंपनी को लीज पर सौंप कर उसे इतना अधिकार दे देता है, जितना ईस्ट इण्डिया कंपनी को था। ...याचिका में कहा गया है कि ७० वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे लोग आज तक अपना मकान यहां इसलिए नहीं बना सके हैं, क्योंकि यहां उन्हें कंपनी से अपना मकान बनाने की अनुमति नहीं है।

जवाहर शर्मा की इस याचिका के उत्तर में टाटा प्रबंधन ने भी लंबा-चौड़ा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में टाटा प्रबंधन ने जवाहर शर्मा के सभी आरोपों को गलत बताया है। टाटा प्रबंधन ने अदालत को दिये अपने उत्तर में कहा है कि जमशेदपुर मूलतः एक औद्योगिक शहर है। इसकी स्थापना टाटा कंपनी ने स्वर्गीय जमशेदजी टाटा के दृढ़ संकल्प के तहत की थी। जमशेदपुर की स्थापना के पांच वर्ष पूर्व जमशेदजी टाटा ने अपने बेटे दोराबजी टाटा को १९०२ में ही अपने सपनों के शहर जमशेदपुर के बारे में एक पत्र लिखकर इच्छा व्यक्त की थी, "गलियों व सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाये जायें। बगीचे व मैदान के लिए यहां काफी जगह है। फुटबाल, हॉकी व पार्क के लिए एक बड़े हिस्से को आरक्षित किया जाये। मंदिर, मस्जिद और चर्च के लिए भी स्थान हो।" टाटा कंपनी ने अपने जवाब में जमशेदजी टाटा के इस पत्र का उद्धरण देते हुए कहा है कि इस शहर के संस्थापक की उपर्युक्त भावना का खयाल सदैव कंपनी ने किया। टाटा-प्रबंधन ने १९७९ में पटना उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज जितेन्द्र नारायण के नेतृत्व में इस शहर की स्थिति के संबंध में गठित तीन सदस्यीय जांच-समिति की टिप्पणी को भी उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है, "जमशेदपुर शहर पटना से ४३१ किलोमीटर की दूरी पर है। यह समुद्र तल से ५३० फीट की ऊंचाई पर है। तकरीबन ६६.८२ वर्गमील के क्षेत्र में फैले इस शहर की आबादी ७.५३ लाख है। इस आधुनिक शहर में अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पार्क, बाजार व सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।" टाटा कंपनी ने आगे अपने जवाब में कहा है कि यद्यपि जुगसलाई में नागरिकों द्वारा निर्वाचित नगरपालिका है, 'फिर भी कंपनी सरकार के पीएचडी विभाग के सहयोग से वहां भी जलापूर्ति करती है। इसी तरह मानगो क्षेत्र में भी कंपनी १.५ लाख गैलन जल की आपूर्ति करती है।

> **शहर के लोगों की बस एक ही मांग है कि आठ लाख की आबादीवाली इस इस्पात नगरी में एक अदद निर्वाचित नगर निगम की सरकार व्यवस्था करे।**

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कंपनी शहर की नागरिक सुविधाओं के प्रति कितनी तत्पर है। टाटा कंपनी ने उत्तर में कहा है कि कंपनी की नगर प्रबंधन की कुशलता के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमशेदपुर को 'भारत का तीर्थस्थल' की संज्ञा दी थी। कंपनी के जवाब में इस तरह के अनगिनत उद्धरण पेश किये गये हैं और नगर निगम की मांग को शहर के हित के विरुद्ध करार देते हुए कंपनी ने जवाब में यह भी कहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डा० श्रीकृष्ण सिंह के कार्यकाल के दौरान भी नगर निगम की बात उठी थी, पर डा० श्रीकृष्ण सिंह ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था कि जमशेदपुर में नगर निगम का गठन कर मैं इस शहर को दूसरा पटना नहीं बनने देना चाहता। सरकार इस विचार पर सदैव कायम रही कि नगर की सभी सेवाओं की जिम्मेदारी पूर्ववत कंपनी के जिम्मे ही रहे।"

टाटा कंपनी ने कोर्ट में दिये अपने जवाब में याचिका दायर करनेवाले जवाहर शर्मा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जवाहर शर्मा एक व्यवसायी हैं, जिनके 'कमला इंजीनियरिंग वर्क्स' और अन्य व्यवसाय चलते हैं। जवाहर शर्मा 'टेल्को' एवं 'टाटा राबिसन फ्रेजर लिमिटेड' में सामान की आपूर्ति करते रहे थे। १९७८ में कंपनी ने उनकी फर्म के आपूर्ति के आदेश को रद्द कर दिया। १९८१ से १९८५ तक जवाहर शर्मा ने कंपनी से रद्द आदेश को पुनः जारी करने का अनुरोध किया। नतीजतन, कंपनी ने फिर सीमित मात्रा में उनकी आपूर्ति प्राप्त करनी शुरू की। इससे उन्हें निराशा हुई और उसी नाराजगी के तहत उन्होंने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की।" कंपनी के इस आरोप को जवाहर शर्मा नकारते हुए 'माया' से कहते हैं, "कंपनी का यह आरोप बौखलाहट भरा है।"

बहरहाल, एक तरफ जहां नागरिक सुविधाओं के सवाल पर टाटा-प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष जारी है, वहीं शहर के जुगसलाई क्षेत्र में सरकारी नगरपालिका के कुप्रबंध के विरुद्ध भी लोग उत्तेजित हैं। जुगसलाई भाजपा संघर्ष समिति के संयोजक रतन जोशी 'माया' से कहते हैं, "जुगसलाई इलाके में भी पानी, बिजली, सफाई, चिकित्सा आदि की गंभीर समस्या है।"

जमशेदपुर हर कोने से अपने हकों के लिए बहसतलब है। हक के सवाल पर छिड़े इस बहस-मुबाहिसे का निदान कब तक और क्या निकलता है, यह देखना है।

—विकास कुमार झा

छाया: प्रभाकर

गिरोहों की गिरफ्त में जमशेदपुर

इस्पातनगरी जमशेदपुर में गुंडा गिरोहों का कैसा खूनी टकराव चल रहा है?

गुंडा गिरोहों के खूनी टकराव ने जमशेदपुर को दहशत से बुरी तरह जकड़ रखा है। जहां अकूत धन और समृद्धि होती है, शातिर अपराधियों के फलने-फूलने की उर्वरता भी वहां मौजूद रहती है। गरीब बिहार की इस वैभवशाली औद्योगिक नगरी की भी यही दुखद नियति है, जहां के बाशिंदे प्रतिपल आतंक की आहट से स्तब्ध रहते हैं। दिन-दहाड़े या सरेशाम कब-किस पल दोतरफा गोली-बमों की बौछार शुरू हो जायेगी और लाशें बिछ जायेंगी यह आशंका शहर के हर आदमी को सहमाये रखती है। विगत २ फरवरी को ऐसे ही एक सनसनीखेज खूनी वाकये में ज़मशेदपुर युवा इंका के अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्र सहित आनंद राव व जनार्दन चौबे की हत्या हो गयी, तो जमशेदपुर एक बार फिर दहल गया। ३ फरवरी को इस हत्याकांड के विरोध में सारा जमशेदपुर शहर बंद रहा। प्रदीप मिश्र के परिवार की जमशेदपुर के सामाजिक जीवन में अच्छी खासी प्रतिष्ठा रही है। प्रदीप के पिता स्व० बद्रीनारायण मिश्र शहर के एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता थे और लगभग तेरह वर्षों तक वे अधिसूचित क्षेत्र की समिति के उपाध्यक्ष भी रहे थे। ढाई वर्ष पूर्व प्रदीप जमशेदपुर युवा इंका के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे और थोड़े ही समय में प्रदीप ने भी अपनी अच्छी पहचान कायम कर ली थी। शायद इसलिए जमशेदपुर के अधिकांश लोगों का कहना था कि अगर सिर्फ आनंद राव व जनार्दन चौबे का खून हुआ होता, तो शहर इतना मातम नहीं मनाता, क्योंकि आनंद राव और जनार्दन चौबे का नाम जमशेदपुर के लिए आतंक का पर्याय था। पर इन दोनों के संग हत्यारों ने क्योंकि प्रदीप मिश्र को भी मौत के घाट उतार दिया, इसलिए सभी लोग विचलित हो उठे।

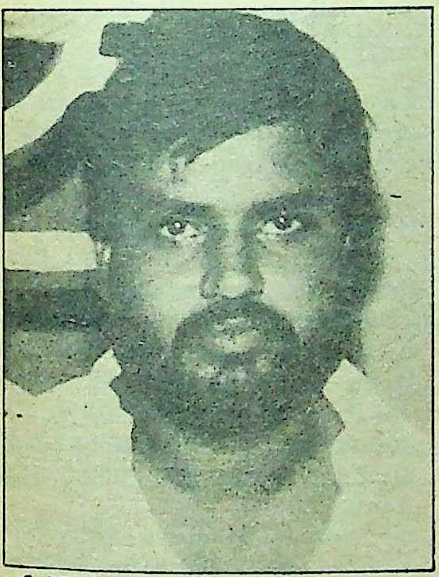

सुनियोजित साजिश के शिकार: प्रदीप

घटना: २ फरवरी का यह खून-खराबा गुंडा गिरोहों के टकराव की ही परिणति था। अकसर बड़ी ठेकेदारी अपने-अपने हिस्से में लेने के लिए गिरोहों की हिंसक मुठभेड़ इस शहर के लिए आम बात है। पर प्रदीप मिश्र जिनका ठेकेदारी आदि से कोई सरोकार नहीं था, आखिर हत्यारों का निशाना क्यों बने, यह सवाल सबको परेशान किये हुए है, लिहाजा, तरह-तरह के तर्क उभर रहे हैं। पुलिस जहां यह मानती है कि हत्यारे महज आनंद राव और जनार्दन चौबे से बदला लेना चाहते थे और उसी क्रम में निर्दोष प्रदीप भी धोखे से हत्यारों के शिकार हो गये, वहीं जमशेदपुर के राजनीतिक गणितज्ञ यह जोड़-घटाव कर फलाफल निकाल रहे हैं कि ठेकेदारी व राजनीतिक रंजिश का संयुक्त प्रसंग इस घटना की पृष्ठभूमि में है। प्राथमिकी के आधार पर जुगसलाई पुलिस ने धारा-३०२, ३०७/३४ आदि के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जिला कांग्रेस किसान सेल के अध्यक्ष पारसनाथ सिंह और उनके भाई सुशील कुमार सिंह जो जमशेदपुर युवा इंका के उपाध्यक्ष हैं को इस हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जुगसलाई थाने के आरक्षी निरीक्षक एसके राय 'माया' से कहते हैं, "यह घटना आनंद राव और साहेब सिंह के बीच चली आ रही ठेकेदारी की लड़ाई को लेकर हुई। दोनों अरसे से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। प्रदीप मिश्र की हत्या महज इसलिए हो गयी, क्योंकि घटना के समय वे आनंद राव के साथ गाड़ी में बैठे थे।" जमशेदपुर के सिटी एएसपी केएन चौबे के अनुसार, "आनंद राव, पारसनाथ सिंह, सुशील सिंह, साहेब सिंह, वीरेंद्र सिंह, कल्लू सिंह और दशरथ सिंह आदि की ठेकेदारी यहां चलती रही है। स्क्रैप और शराब आदि का इनका ठेका रहता है। आनंद राव पहले रेलवे में ठेकेदारी करता था। पर जब उसने ठेकेदारी मे अपना हाथ-पांव फैलाना शुरू किया, तो टकराव शुरू हो गया। २ फरवरी की घटना में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है वे जमशेदपुर के नहीं लगते।"

प्रदीप मिश्र जिनका ठेकेदारी आदि से कोई सरोकार नहीं था, आखिर हत्यारों का निशाना क्यों बने, यह सवाल सबको परेशान किये हुए है, लिहाजा, तरह-तरह के तर्क उभर रहे हैं। पुलिस जहां यह मानती है कि हत्यारे महज आनंद राव और जनार्दन चौबे से बदला लेना चाहते थे और उसी क्रम में निर्दोष प्रदीप भी धोखे से हत्यारों के शिकार हो गये, वहीं जमशेदपुर के राजनीतिक गणितज्ञ यह जोड़-घटाव कर फलाफल निकाल रहे हैं कि ठेकेदारी व राजनीतिक रंजिश का संयुक्त प्रसंग इस घटना की पृष्ठभूमि में है।

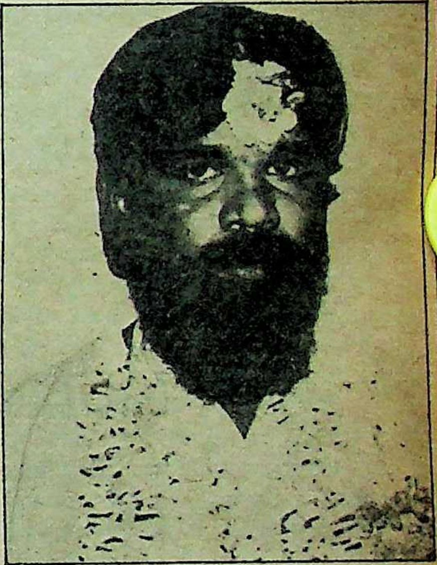

आतंक का खमियाजा: आनंदराव

कारण: क्या सचमुच हत्यारे सिर्फ आनंद राव से ही अपनी अदावत का हिसाब चुकता करना चाहते थे? जानकारों का कहना है कि हत्यारों की नजर तीनों पर थी और प्रदीप मिश्र की हत्या इत्तफाक नहीं, बल्कि सुनियोजित ढंग से हुई। हत्यारे अरसे से इस ताक में थे कि कब आनंद राव, जनार्दन चौबे और प्रदीप मिश्र की तिकड़ी एक संग हाथ लगे कि एक ही बार में सबको साफ कर दिया जाये। इस हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार पारसनाथ सिंह

साधनों की कमी: एएसपी चौबे

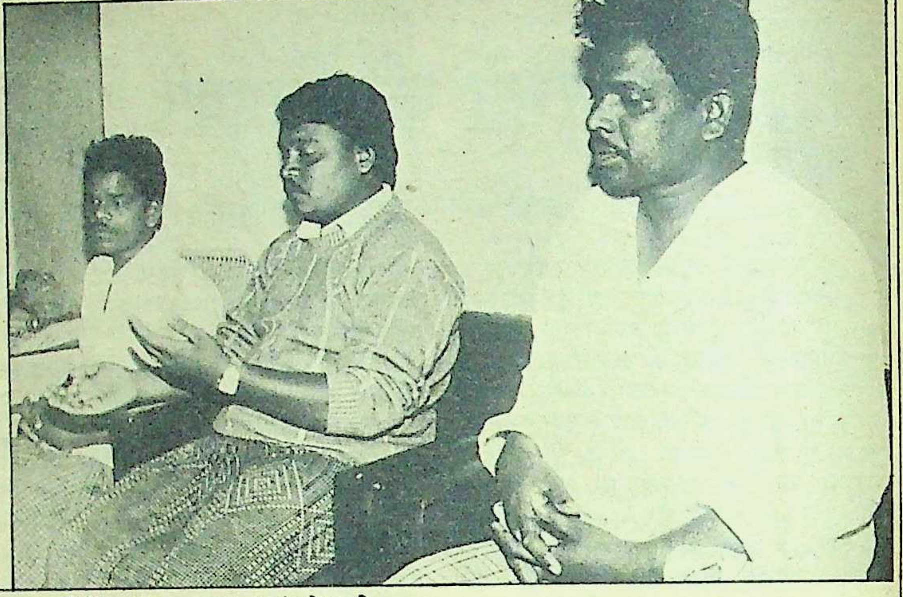

वह गरीबों का मददगार था: आनंद के भाई

परमात्मानंद मिश्र

> "आनंद राव से प्रदीप की कोई अंतरंगता नहीं थी। बस सामान्य सा परिचय था। ठेकेदारी आदि से भी प्रदीप या हमारे परिवारं के किसी सदस्य का संबंध नहीं रहा। हमारी आरा मशीन है और चूने का भी व्यवसाय चलता है जो हमारे परिवार की रोजी-रोटी का साधन है।"

और सुशील सिंह की आनंद राव से क्यों ठनी थी इसका खुलासा करते हुए जमशेदपुर की पुलिस का कहना है कि शहर के नामी ठेकेदार संकटा सिंह के इन दोनों बेटों से आनंद राव का सदैव कोई-न-कोई मामला चलता ही रहता था। जनार्दन चौबे आनंद राव का दायां हाथ था जो आनंद के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरता था। जानकारों के मुताबिक, सुशील सिंह जमशेदपुर युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष होने के नाते काफी दिनों से प्रयासरत था कि प्रदीप को किसी तरह अपदस्थ कर वह अध्यक्ष पद पर काबिज हो जाये। बहरहाल, पुलिस ऐसी अनेक संभावनाओं को लेकर माथा-पच्ची कर रही है। पुलिस उन सभी मामलों पर नजर डाल रही है, जिनमें आनंद राव की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिरकत थी। जुगसलाई के चौक बाजार स्थित एक मंदिर के विवाद का प्रसंग भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चौक बाजार में गौरीशंकर रोड के निवासी रोशन अली की एक खाली जमीन थी। इस जमीन पर जिंदे नामक एक दादा ने कब्जा कर लिया। कहते हैं कि जिंदे से बदला लेने के लिए रोशन अली ने आनंद राव को ठीक किया। आनंद राव ने एक दिन जिंदे को इस जमीन से खदेड़ कर भगा दिया। तो क्या जिंदे ने इसका बदला लेने के लिए यह कांड किया? लेकिन कुछ लोग इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि यह सही है कि जिंदे व आनंद राव के बीच तनाव था, इस कांड में जिंदे का ही हाथ है, यह कहना कठिन है।

आनंद राव को जमशेदपुर का 'वरदाभाई' कहा जाता था। ३२ वर्षीय आनंद आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कटलापुरी गांव का मूल निवासी था। उसके पिता सीएच तविटय्या रेलवे की नौकरी के दौरान जमशेदपुर आये थे और फिर तभी से आनंद का परिवार हमेशा के लिए यहीं बस गया। आनंद राव और उसके भाई अप्पा राव ने १९८४ से रेलवे में जोर-शोर से ठेकेदारी शुरू की। आनंद के अन्य दो भाई कृष्णा राव और कामेश्वर राव रेलवे की नौकरी में हैं।

जमशेदपुर की लोको कालोनी में वाकई जमशेदपुर के इस दिवंगत डॉन को बहुतेरे लोग आज भी विह्वलता से याद करते हैं, क्योंकि आतंक से अर्जित पैसे वह जरूरतमंदों को भी गाहे-बगाहे दिया करता था। कुछ अटकलबाजों का यह भी तुक्का है कि प्रदीप आनंद राव की मदद ठेकेदारी के काम में करते थे और फलस्वरूप आनंद से उन्हें आर्थिक मदद मिलती थी। पर इन अटकलों को नकारते हुए प्रदीप के अग्रज परमात्मानंद मिश्र 'माया' से कहते हैं, "आनंद राव से प्रदीप की कोई अंतरंगता नहीं थी। बस सामान्य सा परिचय था। ठेकेदारी आदि से भी प्रदीप या हमारे परिवार के किसी सदस्य का संबंध नहीं रहा। हमारी आरा मशीन है और चूने का भी व्यवसाय चलता है जो हमारे परिवार की रोजी-रोटी का साधन है।"

अपराध के मामले में जमशेदपुर रांची व धनबाद के 'ग्राफ' को तेजी से छू रहा है। १९८७ में ही यहां कई महत्वपूर्ण लोगों की हत्या हुई और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। लिहाजा, गिरोहों का हौसला बढ़ता गया। १९ जून, १९८७ को भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता बसंत साहू का खून सोनारी में कर दिया गया। ८ अगस्त १९८७ को निर्मल महतो की जान भी गयी। फिर २९ सितंबर, १९८७ को चर्चित पत्रकार मोहम्मद इलियास की हत्या ने सब को स्तब्ध कर दिया। यह सिलसिला आज तक जारी है। बलात्कार व डाकाजनी की वारदातें अब यहां के लिए रोजमर्रे की बातें हैं। जमशेदपुर में बेलगाम अपराध कभी नियंत्रित हो सकेगा, इसकी उम्मीद यहां के लोग छोड़ चुके हैं।

छाया: प्रभाकर

—विकास कुमार झा

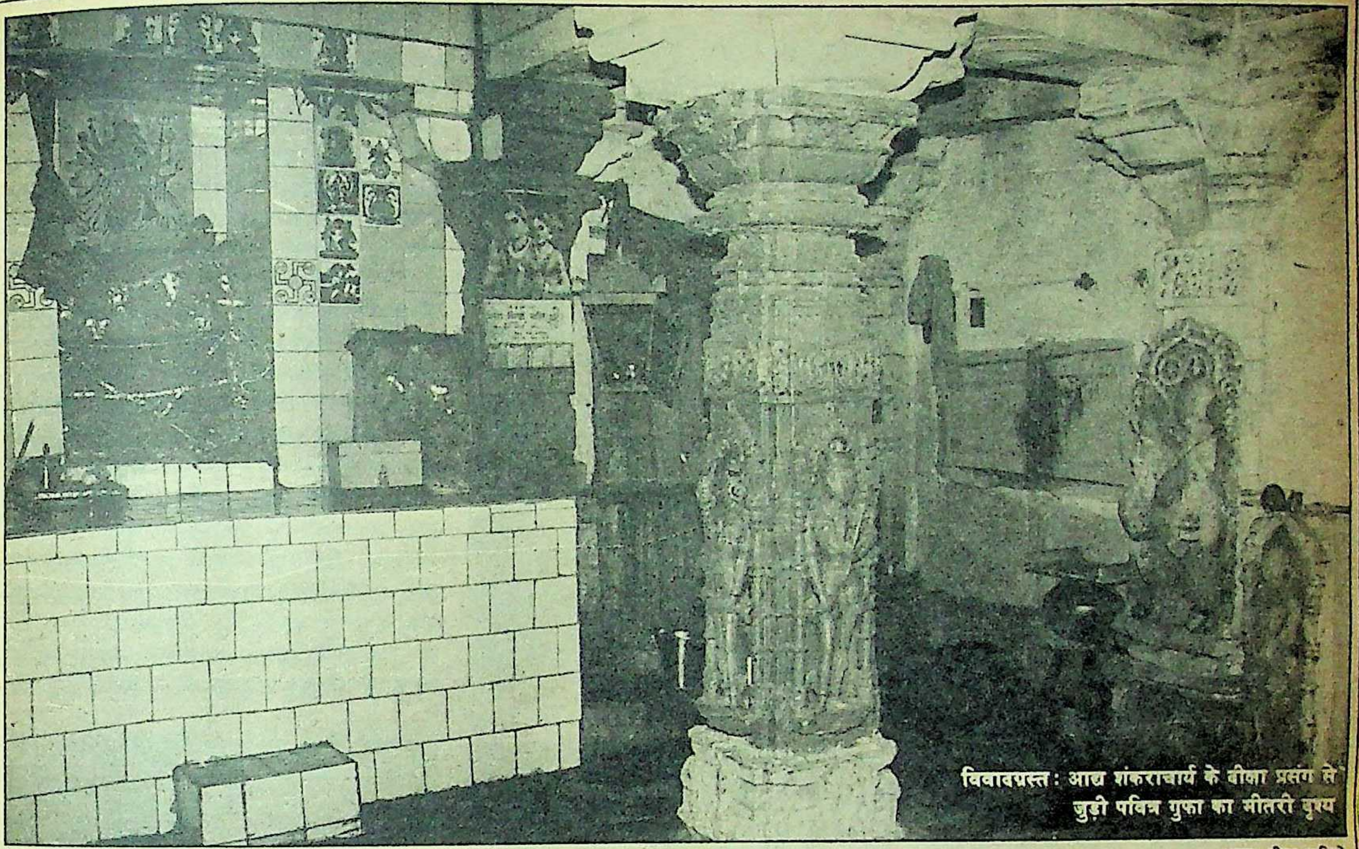

विवादग्रस्त: आद्य शंकराचार्य के दीक्षा प्रसंग से जुड़ी पवित्र गुफा का भीतरी दृश्य

छाया: वीणा स्टूडियो

आद्य शंकराचार्य का दीक्षा-स्थल

शंकराचार्यों में विवाद क्यों है ?

आज से करीब १२ सौ वर्ष पूर्व आद्य शंकराचार्य ने नर्मदा के तट पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के समीप जिस गुफा में स्वामी गोविंद भगवत्पाद से गुरुदीक्षा ली थी, उस गुफा की खोज १९७७ में तमिल लेखक एएन शर्मा ने की थी। दस साल बाद १९८७ में कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने इस गुफा और आसपास के क्षेत्र को जब से खरीदा है, तभी से एक अन्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस गुफा को असली मानने से इनकार कर दिया है। इधर करीब तीन दर्जन वर्तमान व भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि सभी शंकराचार्यों का सम्मेलन बुलाकर गुफा की असलियत का पता लगाया जाये। यह गुफा आखिरकार विवाद का मुद्दा क्यों बन गयी है ? :

वैचारिक द्वंद्व में एक ओर हैं, कांची कामकोटि पीठम के जगदगुरु जयेंद्र सरस्वती स्वामी और दूसरी ओर हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगदगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। दोनों शंकराचार्यों के मध्य विवाद के मूल में है, नर्मदा के तट पर महेश्वर तीर्थ में स्थित वह प्राचीन गुफा जिसके बारे में मान्यता है कि वहां आद्य शंकराचार्य ने अपने गुरु से दीक्षा ली थी।

सुदूर केरल में कालडी में नम्बूद्री ब्राह्मण दंपत्ति—आर्यम्बा और शिवगुरु के यहां जनमे आद्य शंकराचार्य के बारे में यह तथ्य निर्विवाद है कि वह गुरु की खोज में अल्पायु में ही घर से निकल पड़े थे। उनकी यह तलाश अंततः नर्मदा के तट पर बसे ओंकारेश्वर में पूरी हुई, जहां उन्हें गोविंद भगवत्पाद के दर्शन हुए। ओंकारेश्वर में अवस्थित किसी गुफा में शंकर ने दीक्षा ली और संन्यास ग्रहण किया।

गुफा की खोज : इस पवित्र एवं ऐतिहासिक गुफा के साथ आश्चर्यजनक तौर पर एक स्वप्न का प्रसंग जुड़ा हुआ है। १९७७ में कांची कामकोटिपीठम के परमाचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती को स्वप्न आया कि गोविंद भगवत्पाद की वह गुफा ओंकारेश्वर में है, जहां आद्य शंकराचार्य ने दीक्षा ली थी। इस गुफा की खोज का दायित्व उन्होंने तमिल लेखक एएन शर्मा को सौंपा जो उस समय मप्र विद्युत मंडल में कार्यरत थे। बताते हैं कि पीठ ने शर्मा को साहित्य, धन व साधन भी मुहैया किये, किंतु गुफा की खोज के बाद न जाने क्यों वे कांची कामकोटि पीठम के बजाय ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ के पास चले गये और उन्हें अपने साथ ओंकारेश्वर लाये। दोनों शंकराचार्यों ने गुफा को वर्णित वास्तविक गुफा स्वीकारा। इन्हीं दिनों देश की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में तत्संबंधित लेखादि भी प्रकाशित हुए। गुफा की खरीद व व्यवस्था आदि के लिए उस समय आद्य शंकराचार्य स्मारक न्यास का भी गठन हुआ, लेकिन पहल और प्रारंभिक सक्रियता के बाद इससे मुंह मोड़ लिया गया और मामला अधर में लटक गया।

खरीदी : एमजीके मेनन पेशे से पत्रकार हैं और राजधानी से एक अंग्रेजी साप्ताहिक निकालते हैं। मेनन श्री कांची कामकोटि पीठम सेवा ट्रस्ट के संस्थापक व सचिव हैं। इस ट्रस्ट के हाथों में संप्रति उपरोक्त गुफा एवं समीपवर्ती गोविंदेश्वर मंदिर का

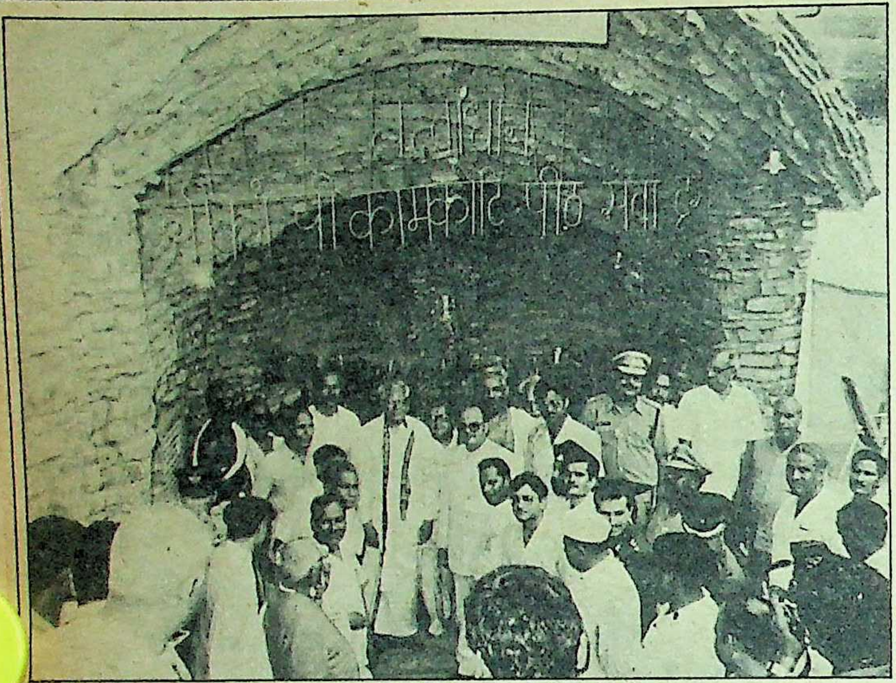

आकर्षण व आस्था का केंद्र: पवित्र गुफा में राष्ट्रपति वेंकटरमण और अर्जुन सिंह

स्वामित्व है। १९८१ में मेनन गुरुवायुर गये, तो शंकराचार्य से मिले। पारस्परिक चर्चा में गुफा का भी उल्लेख हुआ। मार्च १९८७ में जयेंद्र सरस्वती भोपाल आये, तो बात आगे बढ़ी। योजना को मूर्त रूप देने के लिए उक्त ट्रस्ट का गठन किया गया और जुलाई १९८७ में उसका पंजीयन भी हो गया। इस ट्रस्ट के सदस्यों में पुलिस महानिदेशक एम नटराजन, मप्र विद्युत मंडल के चेयरमैन टीएस सेतुरत्नम, एस लक्ष्मीनारायण, आईएएस, शैलेंद्र सिंह, एन सुब्रह्मण्यम, एमटी महाजन, दिनेश अवस्थी, एमपी गुप्ता, बीएस शर्मा, जयनारायण पुरोहित एवं कलेक्टर, खंडवा शामिल हैं।

१९८७ से पहले उपरोक्त गुफा को लोग काली माता की गुफा के नाम से जानते थे। नर्मदा नदी के किनारे घाट से ऊपर को जानेवाले रास्ते के दायीं ओर की सीढ़ियों के बगल में यह गुफा स्थित है। पश्चिमोन्मुख इस गुफा में भीतरी छत अलंकृत है और गुफा को ढहने से बचाने के लिए प्रस्तर स्तंभ भी खड़े किये गये हैं। छत और स्तंभों पर उत्कृष्ट शिल्प उत्कीर्ण है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गुफा ने सदियों नर्मदा और काल के थपेड़े सहे हैं। यह गुफा और समीपवर्ती घाट खरीदी के पहले तक महंत मणि गिरि की निजी संपत्ति थे। यह संपत्ति महंत को पुरखों से विरासत में मिली थी और यही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी थी। महंत मणि गिरि के देहावसान के बाद इसकी देखभाल उसकी विधवा पत्नी सरस्वती बाई करने लगी।

गुफा असली नहीं है: शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती

गुफा असली है: कांची के शंकराचार्य जगद्गुरु जयेंद्र सरस्वती

१९८७ में जयेंद्र स्वामी के भोपाल आगमन और तदुपरांत ट्रस्ट के गठन के बाद खरीदी की योजना पर तेजी से अमल हुआ और सरस्वती बाई से एक लाख रुपए में सौदा पक्का हो गया। इस बीच इंदौर के एक अधिवक्ता छगनलाल शर्मा ने गुफा के आसपास की जमीन खरीद डाली थी और स्थगन के लिए वह अदालत भी गये। मामले में पेंच और खरीदी के खटाई में पड़ने के डर से तुरतफुरत तेजी से काम हुआ और एक जुलाई को रजिस्ट्री हो गयी। खरीदी की योजना केवल गुफा तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाद में गोविंदपाद के मंदिर तथा कालांतर में मांधाता पहाड़ी पर लगभग दस एकड़ भूमि भी खरीद ली गयी।

आरोप-प्रत्यारोप: इसे दुर्भाग्यजनक ही कहा जायेगा कि खरीदी के बाद से यह प्रकरण विवाद और आरोप-प्रत्यारोपों के जाल में उलझा हुआ है। और-तो-और विधवा सरस्वती बाई का कहना है कि इस सौदे में उन पर दबाव डाला गया और उसके साथ धोखा हुआ। सरस्वती के अनुसार, बड़े साहब लोग उस पर आकर दबाव डालते थे कि अगर उसने गुफा नहीं बेची, तो सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी और उसे एक धेला नहीं मिलेगा। इसी क्रम में उसे रातो-रात खंडवा ले जाया गया और रजिस्ट्री करायी गयी। सरस्वती जिन कुछ लोगों पर दबाव डालने का आरोप लगाती है, उनमें एमटी महाजन भी शामिल हैं। वे कहते हैं कि कहीं कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की गयी। स्वेच्छा से बिक्री की बात को मेनन भी दोहराते हैं। मेनन के अनुसार, "दबाव की बात गलत है। हां, यह जरूर है कि वह पहले पांच लाख रुपए मांग रही थी। काफी दिनों तक उससे सौदेबाजी होती रही। अंततः एक लाख रुपए पर सौदा पटा। रजिस्ट्री में शीघ्रता नीयत में खोट नहीं, वरन तकनीकी कारणों से की गयी।"

गुफा का विवाद सुर्खियों में तब आया, जब स्वामी स्वरूपानंद ने बयान दिया कि खरीदी गयी गुफा असली नहीं है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का कहना था कि यह गुफा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित वह गुफा नहीं है, जिसमें आद्य शंकराचार्य ने गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ली थी। इस बीच, उल्लेखनीय है कि गुफा के दर्शनों के लिए गणमान्य व्यक्तियों का आना-जाना शुरू हो गया था। राज्यपाल केएम चांडी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा १९ नवंबर १९८७ को ओंकारेश्वर गये। अर्जुन सिंह तिबारा मुख्यमंत्री बनकर जब

दिल्ली से भोपाल आये, तो शपथग्रहण के तीसरे दिन १६ फरवरी और फिर २१ अप्रैल, १९८८ को ओंकारेश्वर गये। गुफा का अवलोकन कर उन्होंने वहां पूजा-अर्चना भी की। इसी क्रम में, गत वर्ष २६ जून को राष्ट्रपति आर वेंकटरमण भी गुफा-मंदिर के दर्शनार्थ आये। नवंबर में प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक सलाहकार पुपुल जयकर का ओंकारेश्वर आगमन हुआ और पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी यहां आये।

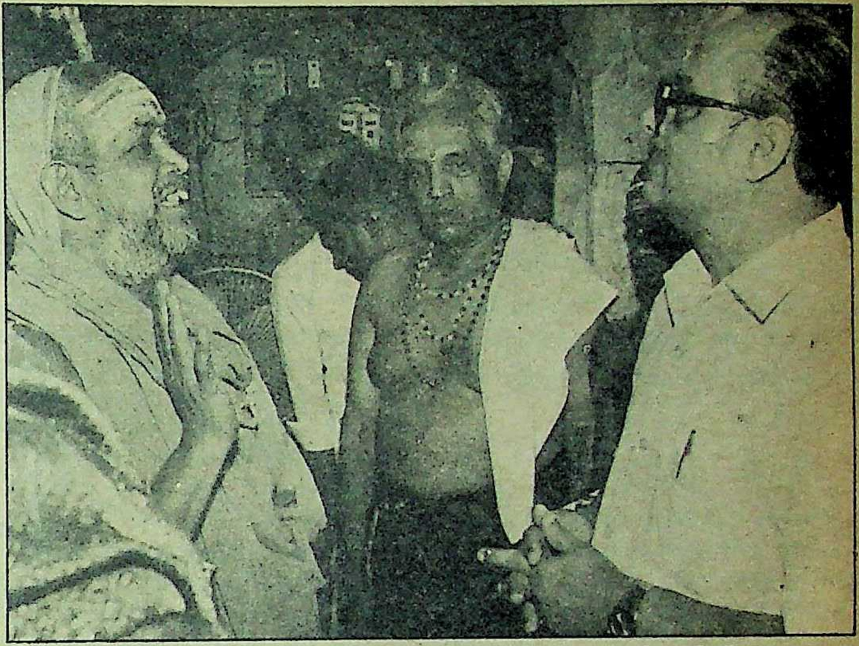

शंकर ज्ञान केंद्र की व्यापक योजना : शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और अर्जुन सिंह

स्वयं शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती भी यह कह चुके हैं कि यही प्रामाणिक गुफा है। उन्हीं के निर्देश पर ट्रस्ट का गठन हुआ है। उनकी मांधाता पहाड़ी पर दसेक एकड़ क्षेत्र में शंकर ज्ञान केन्द्र की स्थापना की योजना है, जिस पर अमल की दिशा में कतिपय कदम उठाये जा चुके हैं।

स्पष्ट है कि स्वामी स्वरूपानंद द्वारा गुफा को नकली निरूपित करने से इसकी प्रतिष्ठा पर आघात लगा और इसकी गौरव गरिमा पर आंच आयी। कांग्रेस-इ के लगभग तीन दर्जन वर्तमान व भूतपूर्व विधायकों ने इस आशय की मांगकर मामले को नया मोड़ दिया कि सभी शंकराचार्यों का सम्मेलन बुलाकर गुफा की असलियत का पता लगाया जाये।

कार्यकारी न्यासी महाजन व सचिव मेनन स्वामी स्वरूपानंद के इस तथ्य को निराधार निरूपित करते हैं कि यह गुफा असली नहीं है। स्वयं शंकराचार्य जयेंद्र स्वामी भी यह कह चुके हैं कि यही प्रामाणिक गुफा है। उन्हीं के निर्देश पर ट्रस्ट का गठन हुआ है। उनकी मांधाता पहाड़ी पर दसेक एकड़ क्षेत्र में शंकर ज्ञान केंद्र की स्थापना की योजना है, जिस पर अमल की दिशा में कतिपय कदम भी उठाये जा चुके हैं। ज्ञान केंद्र के परिसर में वेद पाठशाला, संस्कृत अकादमी, शोध केंद्र, पुस्तकालय, वैदिक गणित संस्थान और योग केंद्र खोला जायेगा। मेनन के अनुसार जीर्णोद्धार व अन्य कामों पर अब तक लगभग छह लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं। जहां तक धन व साधनों की उपलब्धता की बात है, ट्रस्ट को अन्य स्रोतों के अलावा मप्र शासन से भी सहायता मिली है। शासन से उसे अब तक लगभग ८ लाख, ७५ हजार रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

सौदे में कोई दबाव नहीं डाला गया : एमजीके मेनन

संपूर्ण प्रसंग से एक रोचक तथ्य यह भी जुड़ा हुआ है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती आज जिस गुफा को संदेहास्पद व नकली बता रहे हैं, लगभग एक दशक पहले उन्होंने न केवल इसे असली होने का प्रमाणपत्र दिया था, वरन स्वामी अभिनव सच्चिदानंद के साथ मिलकर इसे खरीदने का भी उपक्रम किया था। मेनन ने 'माया' के समक्ष वे कागजात प्रस्तुत किये, जिनसे प्रमाणित होता है कि इन दोनों शंकराचार्यों की ओर से संदर्भित गुफा खरीदने की बातचीत महंत मणि गिरि से की गयी थी और यह सौदा ११ हजार रुपए में तय हुआ था। ८ जनवरी १९७९ को महंत मणि गिरि (जो उस समय जीवित थे) को बतौर बयाना पांच सौ रुपए की रकम भी दी गयी थी। यही नहीं, मार्च १९७९ में स्वरूपानंदजी ने इंदौर के पीएस संतानकृष्णन, राजाराम जोशी और एनएम व्यास को पत्र लिखा था, जिसमें 'गुफा-खरीदी में शीघ्रता करें' के आशय के तार का उल्लेख करते हुए कहा गया था कि जरूरत हो, तो तार भेजकर उनसे पावर आफ अटार्नी (मुख्तारनामा) मंगा ली जाये।

दो शंकराचार्यों के मध्य इस असमाप्त विवाद को बहुतेरे लोग कांग्रेसी नेताओं की शरारत व देन मानते हैं। लेकिन यह बात सरलता से गले नहीं उतरती है। यह जरूर है कि मध्यप्रदेश में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के भक्तों में अनेक राजनेता भी शामिल हैं। इन भक्त राजनेताओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मंत्री-पद पर आसीन हैं। दूसरी ओर, अनेक दक्षिण भारतीय आईएएस अधिकारी कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य के अनन्य भक्त हैं।

सर्वप्रमुख, किंतु अनुत्तरित प्रश्न यह है कि गुफा को पहले वास्तविक ठहराने, फिर खरीदने का प्रयास करने के बाद अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद गुफा की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिन्ह क्यों लगा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें एक दक्षिण भारतीय पीठ की सुदूर मध्यप्रदेश में सक्रियता खल रही है। दोनों प्रतिद्वंद्वी शिविरों से परस्पर विरोधी बयानबाजी अभी जारी है। ट्रस्ट के सचिव के नाते एमजीके मेनन सभी शंकराचार्यों को पत्र लिख चुके हैं कि वे आकर गुफा का अवलोकन करें। आना तो दूर किसी ने आठ माह बीत जाने के बाद भी पत्र का उत्तर देना गवारा नहीं किया। दोनों शंकराचार्य आपसी विचार-विमर्श से अथवा चारों शंकराचार्य गुफा का अवलोकन कर किसी सर्वसम्मत व मान्य निर्णय पर पहुंचेंगे, इसकी संभावना नजर नहीं आती। तो क्या आद्य शंकराचार्य की दीक्षा-स्थली पर विवाद की कालिमा मंडराती रहेगी? यदि ऐसा होता है, तो संशय नहीं कि यह हर दृष्टि से दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

—सुधीर सक्सेना, ओंकारेश्वर से

विपक्ष को इंका का आसरा

अर्जुन सिंह के पराभव और प्रदेश कांग्रेस-इ में मची अंतर्कलह से मध्य प्रदेश के विपक्षी खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गयी है, लेकिन क्या विपक्षी दल इस स्थिति का चुनावी लाभ उठाने की स्थिति में हैं या वे भी प्रदेश कांग्रेस-इ की तरह अंतर्कलह के शिकार हैं? प्रदेश के सशक्त विपक्षी दल भाजपा और नवगठित जनता दल में क्या चुनावी तालमेल संभव हो सकेगा?

मध्यप्रदेश में विपक्ष, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, इन दिनों उत्साह का माहौल है और यह उत्साह अकारण नहीं है। कांग्रेस-इ में दिनो-दिन तेज होता अंतर्कलह तथा हाल में सत्तारूढ़ दल में नेतृत्व परिवर्तन के सिलसिले में हुआ नाटकीय-घटनाक्रम उनके इस उत्साह का एक बड़ा कारण है। भाजपा नेता, चाहे संगठन से जुड़े पदाधिकारी हों या विधायकगण, इन दिनों इंका में पेंग मारती गुटीय राजनीति का जिक्र चटखारे लेकर करते हैं। सत्तारूढ दल को वे 'नौ कन्नौजिये, नौ सौ चूल्हे' की मिसाल मानते हैं। "चतुर्दिक व हर स्तर पर फैले भ्रष्टाचार ने प्रशासन को पंगु बना दिया है", विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी कहते हैं, "जनता बदलाव चाहती है। प्रदेश में अब अगली सरकार भाजपा की बनेगी।"

आम तौर पर कांग्रेसी इसे बड़बोलापन और दिवास्वप्न मानते हैं, मगर विपक्षी नेता आशान्वित हैं। विपक्षियों की चर्चा की धुरी आज भी अर्जुन सिंह हैं। अर्जुन सिंह के परंपरागत प्रतिद्वंद्वी और वर्तमान में मप्र जनता दल के अध्यक्ष विद्याचरण शुक्ल कहते हैं, "अर्जुन सिंह रहते तो चुनावी दृष्टि से हमें फायदा था।" राजनीति के गलियारे में अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा की मैत्री के किस्से खासे चर्चित रहे हैं। अपने तीखे तेवरों के लिए विख्यात पटवा ने 'माया' से कहा, "राजीवजी को साधुवाद कि उन्होंने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर भोपाल भेजा था। उन्होंने हमारा काम हलका कर दिया।" इस बात को जोशी इस तरह आगे बढ़ाते हैं, "अर्जुन सिंह का भ्रष्टाचरण के कारण इस्तीफा हमारी जीत है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का हमारा हौसला भी।" इन बयानों पर गौर करें, तो स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष के नेताओं को अपनी ताकत के साथ-साथ इंका की फूट का भी आसरा है।

ध्रुवीकरण : बीते कल के यथार्थ में झांकें, तो इसमें दो मत नहीं कि मध्यप्रदेश भाजपा के लिए सौभाग्यशाली प्रदेश है। यहां उसकी स्थिति अन्य विपक्षी दलों की तुलना में काफी मजबूत है और उसका व्यापक जनाधार है। प्रदेश में विगत तीन दशकों में हुए क्रमिक ध्रुवीकरण का लाभ अंततः भाजपा को ही मिला है। किसी समय पार्टी का प्रभाव केवल मध्य भारत में ही सीमित था, किंतु शनैः-शनैः उसके प्रभाव का विस्तार एक छोर से दूसरे छोर तक हुआ है। छठे और सातवें दशक में विंध्य में समाजवादी दल का गहरा असर था, लेकिन कालांतर में यह प्रभाव छीजता गया। आज स्थिति यह है कि विंध्य में कांग्रेस-इ को चुनौती देने का काम भी प्रमुख तौर पर भाजपा और कुछ हद तक जनमोर्चे की सक्रियता के कारण अब जनता दल को निभाना होगा।

१९५७ के पहले चुनाव में जनसंघ को ११ सीटें मिली थीं जो १९६२ में ४१ से बढ़कर अगले चुनाव में ९८ तक पहुंच गयीं। तदुपरांत संविद सरकार के दुखद अनुभव ने पार्टी को आघात पहुंचाया और उसे कुल जमा ४८ सीटें ही मिल सकीं। इमरजेंसी के बाद १९७७ के ऐतिहासिक चुनावों में जनसंघ ने भरपूर फसल काटी। जनता पार्टी में उसके घटक के १४१ सदस्य विजयी रहे। इस वर्चस्व के कारण मुख्यमंत्री पद जनसंघ की झोली में गया। १९८० और '८५ के चुनाव में जनसंघ घटक भाजपा के बैनर तले चुनाव-समर में उतरा और उसे क्रमशः ६० और ५८ सीटें प्राप्त हुईं।

> राजनीतिक दृष्टि से मध्यप्रदेश का नसीब इस मायने में अच्छा है कि यहां दलों का दलदल नहीं है। प्रदेश में ध्रुवीकरण सीधे-सीधे कांग्रेस-इ और भाजपा के बीच हुआ है।

राजनीतिक दृष्टि से मध्यप्रदेश का नसीब इस मायने में अच्छा है कि यहां दलों का दलदल नहीं है। प्रदेश में ध्रुवीकरण सीधे-सीधे कांग्रेस-इ और भाजपा के बीच हुआ है। मतों का आकलन करें, तो यह तथ्य उजागर होता है कि मतों में आठ से दस प्रतिशत की घट-बढ़ सत्ता-परिवर्तन का बायस बनती रही है। इंका के लिए १९७७ और भाजपा के लिए १९८५ के चुनाव सर्वाधिक प्रतिकूल रहे, किंतु दोनों ही दलों को अपनी-अपनी गर्दिश में लगभग ३२.५ प्रतिशत मत मिले। इसी के आधार पर भाजपा के कोषाध्यक्ष व प्रभावी नेता कैलाश सारंग कहते "सामान्यतः इंका और भाजपा का वजन तराजू के पलड़े पर बराबर है, लेकिन फिलहाल हम लाभ की स्थिति में हैं। भ्रष्टाचार और इंका सरकार की रीति-नीति से आम जन, खास तौर पर किसान बहुत दुःखी हैं। किसानों को तो बेतरह छला गया है।" सांसद सुभाष यादव की अध्यक्षता में गठित कृषक

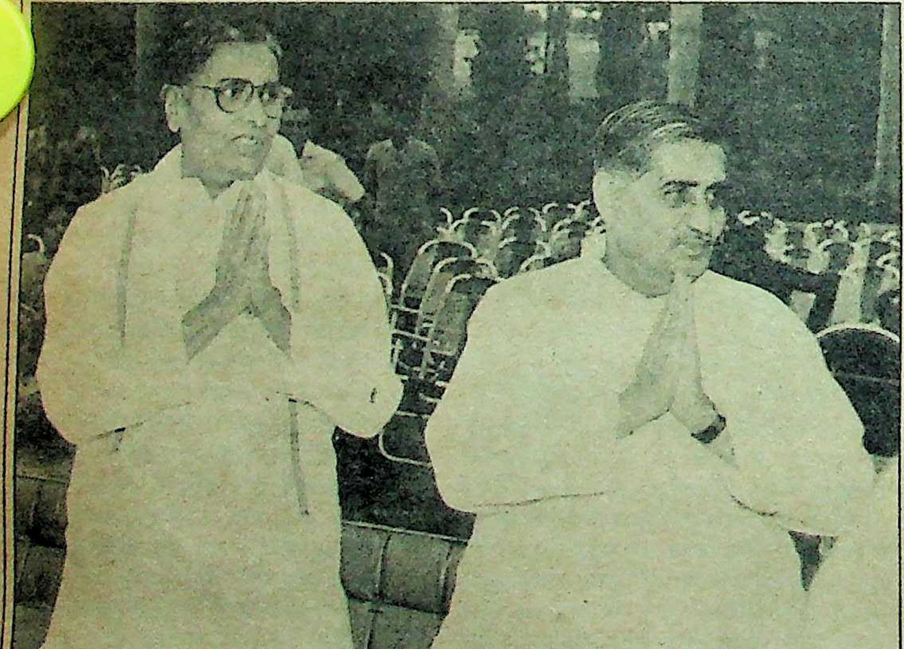

विलय को दूर से नमस्कार: भाजपा नेता सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी

जिस देश में लाखों करोड़ों लोगों के पास सिर छिपाने को छत न हो। मौसम की मेहरबानी पर जहाँ के लोग जिन्दगी गुजारते हों। उसी देश में होती है करोड़ों रुपयों की बरबादी। कारण है हम और आप। हम और आप मिलकर हर साल करते हैं उन करोड़ों रुपयों की बरबादी जिनसे 10 लाख घर इन जैसे ज़रूरतमन्द लोगों के लिये बनाये जा सकते हैं।

दुख की बात तो यह है कि इतना बड़ा सच हमें छूता तक नहीं। कहीं चुभता भी नहीं। क्योंकि हमारे पास कई ज़रूरी चीज़ें हैं सोचने को-करने को। ऐसी फालतू बातों के लिए भला समय कहाँ? हमारी आँखों पर बंधी लापरवाही की पट्टी हमें कुछ देखने नहीं देती।

2000 करोड़ रु० की बरबादी हर साल हो रही है और ये हम सब मिलकर कर रहे हैं।

सड़कों पर, रसोई घरों में, कारखानों और खेतों में। हर जगह, हर कहीं होती है पेट्रोलियम की बरबादी। क्योंकि ज्यादा ईंधन खाने वाले पुराने डिज़ाइन के उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं। सवारी की सही देखभाल नहीं होती। और न ही हमारी आदतों और ड्राईविंग के तरीकों में सुधार।

आपके ज़रा से जागरुक प्रयास से इस फ़ज़ूलखर्ची को रोका जा सकता है। लोगों की सोई हुई चेतना को जगाया जा सकता है। बिखरी हुई आवाज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत बरबादी हो चुकी। अब और नहीं। आइए, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठायें। अपने अखबारों में लिखें। अपनी कॉलोनी, ऑफिस, क्लबों, संस्थाओं – हर तरफ चर्चा करें। काम करने वाले लोगों की सक्रिय टोलियाँ बनायें।

आपकी मदद के बिना कुछ नहीं हो पायेगा। पेट्रोलियम बचाने का संदेश घर-घर तक आपको ही पहुँचाना है।

हम आशा करते हैं कि आप चुप रहने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे।
क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो इस पन्ने को पलट कर कहेंगे – **"मेरी बला से!"**

इस विषय पर आइए हमसे मिलिए। आपके विचारों का स्वागत है।
पेट्रोलियम कंज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन
1008, नई दिल्ली हाऊस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110 001 फोन: 3310006, 3319066

HTA 5372 HIN

कल्याण आयोग को ढकोसला करार देते हुए सारंग कहते हैं, "प्रदेश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है।"

परिवर्तन: एक वक्त था कि भाजपा की विपक्षी दलों में स्थिति सवर्णों की भीड़ में खड़े अछूत जैसी थी। मगर अब इसमें मूलभूत परिवर्तन आया है। इसी को रेखांकित कर पूर्व सांसद प्यारेलाल खंडेलवाल कहते हैं, "भाजपा को अछूत माननेवालों के सोच में परिवर्तन आया है और इसका कारण है भाजपा की ताकत और प्रभाव।" ताकत और प्रभाव का आकलन दुरूह और जटिल कार्य है, मगर भाजपा के प्रति बदले हुए सोच का पता नेताओं के बयानों से लगता है। जनता दल का अध्यक्ष बनने के बाद विद्याचरण शुक्ल राजधानी आकर यह स्पष्ट घोषणा कर गये हैं कि जनता दल भाजपा से चुनावी सहयोग करेगा। भाजपा के शक्तिशाली नेता कुशाभाऊ ठाकरे से उनकी एक से अधिक मुलाकातें भी उपरोक्त बातों की पुष्टि करती हैं।

दूसरी ओर यह तथ्य भी बरकरार है कि भाजपा नेता अपने प्रति विपक्षी नेताओं के बीते कल के सलूक को भुला नहीं सके हैं। जोशी से लेकर पटवा तक एक स्वर में कहते हैं कि भाजपा हर हाल में अपना पृथक अस्तित्व बरकरार रखेगी। आगे वे यह भी कहते हैं कि चुनावी समझौते भी व्यावहारिक धरातल पर होंगे। जोशी दृढ़ता से कहते हैं, "भाजपा अपना पृथक अस्तित्व और अपना चुनाव चिह्न किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी।" वे बताते हैं कि तालमेल के बारे में वे अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को कभी का पत्र लिख चुके हैं, किंतु अभी तक उन्हें किसी का उत्तर नहीं मिला है।

अड़चनें: ऐसा नहीं है कि मध्यप्रदेश में विपक्ष के पक्ष में बयार बह रही है। उनके सामने चुनौतियां हैं और खेमे में परेशानियां भी। आरोपों की कीच और अहम के टकराव से भाजपा भी अब बरी नहीं है। संगठन पर कुछ लोगों खासकर 'चौकड़ी' के हावी होने और चुनाव-कोष में गड़बड़ी के आरोप ने पार्टी की छवि को क्षति पहुंचाने का काम किया है। एक समय जनसंघ या भाजपा सखलेचा-जोशी-पटवा की त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती थी, परंतु यह त्रिमूर्ति अब खंडित हो चुकी है। सखलेचा को शिकायत है कि उनके सहयोगियों ने विपत्ति में उनका साथ नहीं दिया। उनके समर्थक पार्टी के भीतर सखलेचा की छीछालेदर और निष्कासन के लिए सुंदरलाल पटवा को कम दोषी नहीं मानते। गर्दिश के मारे सखलेचा इन दिनों जनता पार्टी में हैं। 'माया' सूत्रों के अनुसार, दिसंबर में सखलेचा ने भाजपा में प्रवेश की नये सिरे से कोशिश की। राजेंद्र धारकर और विक्रम वर्मा आदि कुछेक नेताओं ने राजमाता सिंधिया का भी मन टटोला, पर बात बनी नहीं। एक वक्त के शीर्षस्थ नेता सखलेचा के लिए पार्टी के बंद द्वार बद ही रहे।

पुनः भाजपा-प्रवेश में असफल: वीरेंद्र सखलेचा

विपक्ष आस लगाये बैठा है कि इंका में असंतोष और अंतर्कलह आगत समय में और घना व व्यापक होगा। किस्सा कोताह यह कि विपक्ष की चुनावी संभावनाओं का एक पाया कांग्रेस-इ में व्याप्त आंतरिक विग्रह की जमीन पर टिका हुआ है। देखना है कि उसका कितना लाभ विपक्ष को मिलता है।

भाजपा से तालमेल की कोशिश: विद्याचरण शुक्ल

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गली-कूचों में एक और दुविधा का सामना करना पड़ता है। दुविधा इस मायने में कि अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा की दोस्ती के क़िस्से गलीकूचों में आम हो चुके हैं। "पटवा और सिंह में मैत्री और मिलीभगत में लेशमात्र भी सचाई नहीं है—" जोशी और सारंग ने अलग-अलग भेंट में तकरीबन एक ही शब्दावली में कहा, "सदन में और बाहर अर्जुन सिंह की जितनी तीखी आलोचना पटवा ने की है उतनी किसी और ने नहीं।" इस बारे में विपक्षी नेता तरह-तरह की टिप्पणी करते हैं, मगर सबसे अलग और दिलचस्प टिप्पणी की स्वयं पटवा ने। सवाल दागने पर पटवा ने छूटते ही कहा, "भला सांप और नेवले में दोस्ती हो सकती है? मैंने उन्हें कभी नहीं बख्शा और न ही उन्होंने मुझे। जब मौका आया, उन्होंने मुझ पर वार किया और जब मुझे मौका मिला, मैंने उन पर वार किया।" हाल में अर्जुन सिंह के पराभव और उनकी संकटापन्न स्थिति को देखते हुए आगामी समय में यह देखना यकीनन दिलचस्प होगा कि पटवा और उनकी पार्टी अर्जुन सिंह को किस हद तक आड़े हाथों लेती है?

चुनाव समय पर हों या पहले, मप्र में भाजपा की चुनावी तैयारियां जारी हैं। ग्राम जागरण अभियान इसी का अंग है। पार्टी का नेतृत्व हालांकि अभी भी पुराने जनसंघियों के हाथ में है, किंतु पिछले कुछ सालों में दिलीप सिंह जूदेव और उमा भारती जैसे कुछ नेता परिदृश्य में तेजी से उभर आये हैं। खरसिया में अर्जुन सिंह से बखूबी लोहा लेकर जूदेव पार्टी में 'तुरुप के पत्ते' की तरह उभरे हैं। उन्होंने अर्जुन सिंह को आगामी चुनाव में खरसिया से फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती सार्वजनिक तौर पर दे रखी है।

मप्र में भाजपा ने पांव पसारे हैं, यह सही है, लेकिन अभी भी उसके लिए दिल्ली दूर है। दल के पास प्रभावी आदिवासी नेता का अभाव है और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए उसके पास ले-देकर केवल आरिफ बेग ही बचे हैं। निमाड़ और बुंदेलखंड में पार्टी की जड़ें मध्यभारत के मुकाबले कमजोर हैं। छत्तीसगढ़ में जनता दल के साथ सुविचारित और सुदृढ़ गठबंधन कारगर हो सकता है, अन्यथा मतों का विभाजन भारी पड़ सकता है। विद्याचरण शुक्ल ने यह संकेत दे ही दिया है कि जनता दल कांग्रेस-इ में असंतोष का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेगा। जनता अध्यक्ष को कहीं-न-कहीं यह उम्मीद भी है कि चुनावी भगदड़ में कई कांग्रेसी उनका दामन थामेंगे। दूसरी ओर भाजपा इस तरह के फेर में तो नहीं है, किंतु उसके नेता मानते हैं कि चौराहे पर कांग्रेसी हंडिया फूटने से यानी अंतकर्लह के उजागर होने से जनता में कांग्रेस-इ की छवि मलिन होगी और इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। जाहिर है कि विपक्ष आस लगाये बैठा है कि इंका में असंतोष और अंतर्कलह आगत समय में और घना व व्यापक होगा। किस्सा कोताह यह कि विपक्ष की चुनावी संभावनाओं का एक पाया कांग्रेस-इ में व्याप्त आंतरिक विग्रह की जमीन पर टिका हुआ है। देखना है कि उसका कितना लाभ विपक्ष को मिलता है।

—सुधीर सक्सेना

विद्युत संकट के कगार पर

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का घाटा ४०० करोड़ तक पहुंच गया है। बिजली की हालत यह है कि सरकार दावा तो करती है किसानों को १०-१२ घंटे बिजली देने का, लेकिन असलियत में ३-४ घंटे ही बिजली मिलती है। भावी योजनाओं की स्थिति यह है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बसंत साठे ने राजस्थान में प्रस्तावित चार ताप विद्युत योजनाओं को अव्यावहारिक बताकर रद्द कर दिया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भयंकर बिजली संकट से मुक्त हो सकेगा? विद्युत मंडल की दुर्व्यवस्था का कारण क्या है?

सदी के अभूतपूर्व अकाल से जूझने के बाद अब राजस्थान को अपूर्व विद्युत संकट से गुजरना पड़ेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वसंत साठे ने राजस्थान में प्रस्तावित चार ताप विद्युत परियोजनाओं को अव्यावहारिक बताते हुए उन्हें रद्द करने की घोषणा करके राज्य के सामने विद्युत आपूर्ति का अंधकारमय भविष्य प्रस्तुत कर दिया है। दूसरी ओर जनता दल के सोलह विधायकों ने राज्य की विद्युत समस्या के बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ज्ञापन देकर विद्युत आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था पर चिंता प्रकट की है। इधर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्तमान अध्यक्ष आरसी दवे का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, तो उधर एक सहायक अभियंता तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इंजीनियर्स एसोसियेशन के महासचिव सीताराम गुप्ता ने मण्डल अध्यक्ष पर गम्भीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा देकर विद्युत मण्डल को विवाद के घेरे में ला खड़ा किया है।

चार परियोजनाएं रद्द: राज्य सरकार ने तीन वर्ष तक सर्वे करवाकर अनुमानित लागत के विवरण सहित सूरतगढ़, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ और धौलपुर में कोयले पर आधारित चार बिजली घर लगाने का प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था। इनके पूरे होने पर राज्य को १८८० मेगावाट बिजली उपलब्ध होती, जो राज्य की भविष्य की योजनानाओं की आपूर्ति करने में पूर्ण सक्षम थी। इनमें सूरतगढ़ में ४२० मेगावाट क्षमता की प्रस्तावित परियोजना पर ४६४ करोड़ रुपए, चित्तौगढ़ में ४२० मेगावाट क्षमता की परियोजना पर ४५१.८६ करोड़ रुपए, मांडलगढ़ की ६३० मेगावाट क्षमता की परियोजना पर ८५४.७४ करोड़ रुपए तथा धौलपुर में ४१० मेगावाट क्षमता की परियोजना पर ६४६.११ करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया था। परन्तु २० जनवरी को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वसंत साठे ने कोटा में गैस विद्युत परियोजना का उद्घाटन करते हुए उक्त चारों परियोजनाओं को रद्द करने की घोषणा करके राज्य के विद्युत आपूर्ति के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। उन्होंने उक्त परियोजनाओं को रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि ये प्रस्तावित परियोजनाएं अव्यावहारिक हैं तथा कोयले की ढुलायी का मार्ग भी तय नहीं होने के कारण इन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। उन्होंने केंद्र की विद्युत उत्पादन नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम सस्ती दर पर विद्युत उत्पादन करना चाहते हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
विद्युत भवन, जयपुर

अंधेरे में: राजस्थान राज्य विद्युत मंडल

किंतु विद्युत मण्डल के अध्यक्ष आरसी दवे ने परियोजनाओं को रद्द किये जाने की सूचना से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए बताया, "धौलपुर परियोजना तो पर्यावरण विभाग की आपत्ति के कारण रुकी पड़ी है। विभाग का कहना है कि इससे उत्पन्न प्रदूषण से ताजमहल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है।" केंद्रीय मंत्री के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए दवे ने दावा किया कि वे पूरा प्रयास कर रहे हैं और परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर पूर्ण आशान्वित हैं। दवे ने माया को बताया, "विद्युत मण्डल राज्य के विकास के लिए चिंतित है, उक्त परियोजनाओं के रद्द होने की स्थिति में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को आल्टरनेट व्यवस्था करनी होगी, दूसरे राज्यों में शुरू होने वाली परियोजनाओं में हमारा हिस्सा बढ़ाना होगा।" वे दावा करते हैं कि राजस्थान की स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है तथा विद्युत मण्डल भविष्य की चुनौतियों से निबटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

विधायकों का विरोध: राजस्थान में विद्युत आपूर्ति की समस्या पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए जनता दल के सोलह विधायकों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें बिजली की कमी पर चिंता प्रकट करते हुए शिकायत की गयी है कि राज्य के किसानों को मात्र ३-४ घंटे ही बिजली मिल पाती है, जबकि सरकार १०-१२ घंटे बिजली देने का दावा करती है। ज्ञापन में चारों कोयला विद्युत परियोजनाओं को अव्यावहारिक बताकर रद्द करने को राजस्थान की जनता के साथ घोर अन्याय करार दिया गया है। ज्ञापन में बिजली के महंगे होने की शिकायत करते हुए कहा गया है कि राजस्थान के किसान को ३६ पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है, जबकि हरियाणा व मध्यप्रदेश के किसानों को १८ पैसे तथा उत्तर प्रदेश के किसानों को १६ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। दूसरी ओर राजस्थान अपनी जरूरत की सिर्फ २१ प्रतिशत बिजली का उत्पादन कर पा रहा है तथा १२ प्रतिशत बिजली अन्य राज्यों से महंगी दर पर खरीदनी पड़ रही है।

ज्ञापन में बताया गया है कि रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण राजस्थान में सतह के पानी का अभाव है, इसलिए सिंचाई व पेयजल के लिए लोगों को भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु भूजल का दोहन भी विद्युत की समुचित आपूर्ति के बिना संभव नहीं है। ज्ञापन में केंद्र सरकार पर राजस्थान के हितों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया गया है। ज्ञापन देने वाले विधायक हैं मोहन प्रकाश, नत्थी सिंह, यदुनाथ सिंह, नारायण राम, रामेश्वर यादव, भंवरलाल शर्मा, जयनारायण पूनिया, मोहन छंगाणी, चुन्नीलाल इंदलिया, लालचंद डूडी, जगमाल सिंह, जगत सिंह, सम्पत सिंह, नवरंग सिंह

और माणकचंद सुराणा।

युवा लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक मोहन प्रकाश चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं, "यही हालत रही, तो पांच साल बाद राजस्थान में बिजली की जबरदस्त कमी हो जायेगी और राज्य में कृषि तथा उद्योग दोनों ही ठप हो जायेंगे। अगर इन स्थितियों से लड़ने की तैयारी आज शुरू करें, तब भी हम कम-से-कम १५ साल पिछड़ जायेंगे।" धौलपुर परियोजना पर पर्यावरण विभाग की आपत्ति को निराधार ठहराते हुए मोहन प्रकाश दावा करते हैं कि भूगोल विज्ञानियों के अनुसार साल में दस दिन भी हवा का रुख धौलपुर से आगरा की ओर नहीं होता है, जबकि धौलपुर से ताजमहल की दूरी ६० किमी है। अगर सरकार ४०० करोड़ रुपए की परियोजना लगाना चाहती है, तो २-४ करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाकर प्रदूषण को रोक सकती है। वे बताते हैं कि धौलपुर में बिजली घर लगाने की राज्य की सबसे आदर्श स्थिति है। टाटा कंसल्टेंसी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार धौलपुर में विद्युत उत्पादन की लागत मात्र ५४.८३ पैसा प्रति यूनिट आयेगी, जबकि वर्तमान में कोटा थर्मल में ८० पैसे तथा अंता में १.५० रुपए प्रति यूनिट की लागत आ रही है। परंतु मण्डल के अध्यक्ष आरसी दवे उक्त आरोपों को भ्रामक बताते हुए हालात में सुधार होने का दावा करते हुए कहते हैं, "१९७८ से ८० तक जब मैं चीफ इंजीनियर था उस समय लोग गाड़ियां भर-भर आते थे, गंगानगर से यहां आकर प्रदर्शन करते थे। परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। निश्चय ही स्थितियों में सुधार हुआ है।'

अभियंताओं में रोष : विद्युत मण्डल की कार्य प्रणाली के कारण अभियंताओं में फैले हुए रोष को अभिव्यक्त करते हुए सहायक अभियंता व मण्डल की इंजीनियर्स एसोसियेशन के महासचिव सीताराम गुप्ता ने २० जनवरी को मण्डल के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मण्डल के अध्यक्ष आरसी दवे राजनीति की रोटियां सेंक कर अपनी कुरसी बचाने में लगे रहते हैं। उनका एक पांव हमेशा दिल्ली में रहता है, इस कारण बोर्ड में अराजकता का माहौल है, जिस किसी अधिकारी ने भी इस बारे में मुंह खोलने की कोशिश की, उसे तरह-तरह से परेशान किया गया, कई अधिकारियों ने तंग आकर नौकरी छोड़ दी। एक सहायक अभियंता ने तो आत्महत्या भी कर ली। मण्डल अध्यक्ष पर मनमानी और भ्रष्टाचार के कारण मण्डल की हालत दिन प्रति दिन खस्ता करने का आरोप लगाते हुए गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड में बढ़े हुए भ्रष्टाचार के कारण उसकी हालत सुधरने के बजाय लगातार और गिर रही है। इस विषय में केंद्र सरकार ने भी समय-समय पर चिंता प्रकट की है।

गुप्ता ने जो आरोप लगाये हैं, उनके अनुसार राजस्थान में बिजली के वितरण में छीजत २६.५६ प्रतिशत है, जो जम्मू-काश्मीर के बाद देश में सबसे अधिक है और इससे बोर्ड को हर साल करोड़ों का घाटा हो रहा है। दवे ने जब कार्यभार संभाला था तब बोर्ड का कुल घाटा मात्र ७२ करोड़ था, जो अब तक बढ़कर ४०० करोड़ से अधिक हो चुका है। इस घाटे की पूर्ति के लिए हर साल बिजली की दरों में वृद्धि की गयी और जनता पर ७० करोड़ का बोझ हर साल डाला गया। दवे ने जब कार्यभार संभाला था, उस समय मात्र ३७ करोड़ रुपए की रकम उपभोक्ताओं पर वसूली के लिए बकाया थी, यह रकम अब तक बढ़ कर १०० करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है, सिर्फ श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल कोटा पर १२.५ करोड़, श्रीराम रेयंस पर १२.२५ लाख, श्रीराम विनायल एंड केमिकल्स कोटा पर ७.२५ करोड़ और मोदी अल्क्लीज अलवर पर सवा करोड़ से ज्यादा राशि बकाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसकी एक मुश्त वसूली नहीं की गयी।

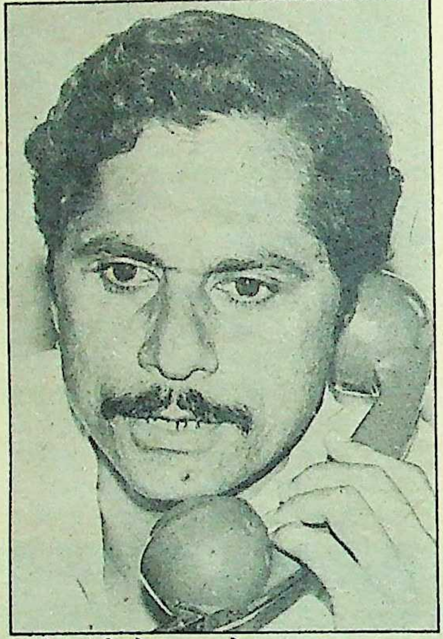
राजीव गांधी को ज्ञापन : मोहन प्रकाश

दवे के कार्यकाल के दौरान हाईटेंशन उपभोक्ताओं की बिजली दर ३० पैसे प्रति यूनिट से बढ़कर १.१० रुपए हो गयी। इसी तरह घरेलू उपभोक्ताओं को ३० पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर ६० पैसे प्रति यूनिट तथा कृषि कार्य के लिए २३ पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर ३७ पैसे प्रति यूनिट चुकाने पड़ रहे हैं। मध्यम उद्योगों को पहले ३८ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती थी, अब ९५ पैसे प्रति यूनिट, लघु उद्योगों को ३५ पैसे प्रति यूनिट के बजाय ८० पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इस दौरान ७०० अभियंताओं को चार्ज शीटें दी गयीं, इससे परेशान होकर कई इंजीनियरों ने नौकरी छोड़ दी। इनमें मुख्य अभियंता एलएन खत्री, उप मुख्य अभियंता यूसी कासलीवाल सहित कई अन्य अभियंता शामिल हैं, एक सहायक अभियंता गुरुदयाल सिंह मिशन ने तो परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दवे के कार्यकाल के दौरान जले हुए ट्रांसफार्मरों को ठीक करने की पांच कार्यशालाएं बंद करवाकर यह काम ठेकेदारों को सौंप दिया गया जिससे मण्डल पर हर साल ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर ४ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा।

गुप्ता ने दवे पर अहमदाबाद की फर्म मैसर्स टेस्ट स्टील कम्पनी तथा एक अन्य फर्म मैसर्स एसआर पार्टनर्स को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने, पेंथर खरीद, श्रीराम केमिकल्स को कनेक्शन देने में घपला सहित कई अन्य आरोप भी लगाये। राज्य में एक दर्जन जगहों पर लगायी जा रही मिनी माइक्रो हाइडिल परियोजना की आलोचना करते हुए गुप्ता ने आरोप लगाया कि माइक्रो प्रोजेक्ट जैसे छोटे बिजली घरों में तो एक मोहल्ले की आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं की जा सकती। गुप्ता ने इसे बोर्ड के पैसे से बिजली घर लगा कर बाद में उद्योगपतियों को बेच देने की साजिश बताया है, ताकि उद्योगपतियों के पास अपने बिजली घर हो जायें। जैसे सूरतगढ़ का माइक्रो प्रोजेक्ट चालू होकर बंद किया जा चुका है।

विद्युत मण्डल के सचिव राजेंद्र जैन ने गुप्ता पर लगे आरोपों का खुलासा करते हुए कहा कि गुप्ता दस वर्षों से भरतपुर में सहायक अभियंता के पद पर थे। इस अवधि में उनके खिलाफ अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं तथा एक मामले में उन्हें सजा भी दी गयी। इसके अलावा कई अन्य मामलों में इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। गुप्ता के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण जुलाई '८८ में उनका स्थानांतरण कुचामन सिटी कर दिया गया था। गुप्ता तभी से अपने पद से अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुप्ता एक ओर अनियमितताओं पर चिंता प्रकट करते हैं, जबकि दूसरी ओर वे नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों व अभियंताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाये।

गुप्ता के आरोपों को झूठा बताते हुए मण्डल के अध्यक्ष आरसी दवे आरोप लगाते हैं कि सीताराम गुप्ता मण्डल प्रशासन को ब्लैकमेल कर रहे थे, ताकि उनके खिलाफ की जा रही जांच बंद कर दी जाये। बिजली की छीजत के आंकड़ों को भी गलत बताते हुए दवे ने दावा किया कि आरोपित आंकड़े १९८० के हैं, १९८७-८८ में छीजत घट कर मात्र २०.५ प्रतिशत रह गयी थी, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। उन्होंने छीजत को तकनीकी ह्रास बताते हुए इसके लिए राज्य की भौगोलिक स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया। कई अभियंताओं के तंग आकर नौकरी छोड़ देने के आरोप का खण्डन करते हुए जैन ने दावा किया कि एक सहायक अभियंता की आत्महत्या का बोर्ड के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं था। दवे ने सभी आरोपों को शरारतपूर्ण व कल्पना की उड़ान करार दिया। राजस्व बकाया के आरोपों के जवाब में सचिव राजेंद्र जैन का कहना है कि बकाया राजस्व की मोटी राशि न्यायालयों से वसूली पर स्थगन आदेशों के कारण अटकी पड़ी है और मण्डल न्यायालयों में लंबित मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने दावा किया कि १९८२ में मण्डल का राजस्व १२० करोड़ रुपए

था, जो चालू वर्ष में ५०० करोड़ रुपए से अधिक है।

विभिन्न अनियमितताओं और घोटालों के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए दवे कहते हैं, "मेरा कोई व्यक्तिगत पावर नहीं है, सारे निर्णय कमेटियां करती हैं। सामान के क्रय की भी निर्धारित प्रक्रिया है और विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग क्रय समितियां हैं। छोटे पावर स्टेशन लगाने की योजना मेरी बनाई हुई नहीं है, बल्कि भारत सरकार की है, ताकि देश के छोटे ऊर्जा स्रोतों का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। छोटे पावर स्टेशनों को निजी उद्योगपतियों को बेचने का आरोप निरी कपोल कल्पना है।

बिजली की दरों में वृद्धि को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए सचिव राजेंद्र जैन कहते हैं कि विद्युत उत्पादन एवं वितरण की लागत में वृद्धि हुई है, कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा काम में लाने वाले उपकरणों व सामान की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा १९८२ तक राज्य को अधिकतर बिजली पन विद्युत योजनाओं से मिलती थी, जो काफी सस्ती पड़ती थी, परंतु अब उपलब्ध अधिकतर बिजली ताप विद्युत घरों से प्राप्त हो रही है, जो अपेक्षाकृत महंगी दर पर उपलब्ध है। जैन ने खेद प्रकट किया कि गुप्ता को अभियंता होने के बावजूद इन सामान्य बातों-का ज्ञान नहीं है।

> राजस्थान में विद्युत आपूर्ति की समस्या पर केंद्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए जनता दल के सोलह विधायकों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें बिजली की कमी पर चिंता प्रकट करते हुए शिकायत की गयी है कि राज्य के किसानों को मात्र ३-४ घंटे ही बिजली मिल पाती है, जबकि सरकार १०-१२ घंटे बिजली देने का दावा करती है।

दवे ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मण्डल की सारी गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा होती रहती है। हर साल प्लानिंग की जाती है, उस पर बहस होती है, भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल के कार्य-कलापों की समीक्षा करते हैं, विद्युत उत्पादन, राजस्व वसूली, छीजत तथा विद्युत दर ये सभी तथ्य भारत सरकार की जानकारी में हैं। आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर भ्रामक रूप देकर प्रचारित करने से सत्य नहीं बदल सकता।

—धीरज कुलश्रेष्ठ

छाया : प्रताप सिंह

आखिर अंधी सरकार ने घुटने टेके !

नेत्रहीन इब्राहीम ने आठ वर्ष तक राजस्थान सरकार और राजस्थान लोकआयोग के अन्याय से जूझ कर अपना हक हासिल किया है। प्रकृति द्वारा शोषित साहसी इब्राहीम ने व्यवस्था के शोषण से कैसे मुक्ति पायी ?

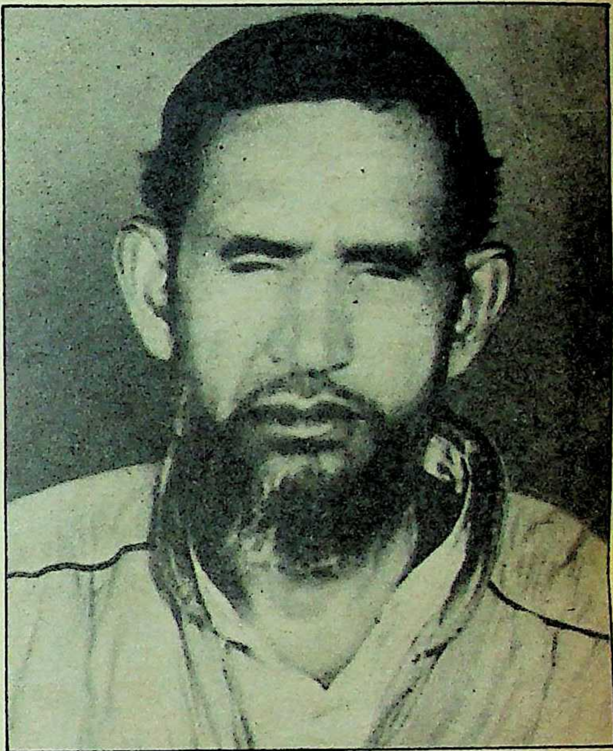

न्याय तो मिला, लेकिन वेतन नहीं : इब्राहीम खां

नेत्रहीन इब्राहीम खां ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि इंसान अगर ठान ले, तो उसे कुछ भी कर गुजरने से कोई नहीं रोक सकता। जन्मांध इब्राहीम ने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद आठ साल तक राजस्थान सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अंततः विधि सहायक के पद पर रोजगार प्राप्त कर जिजीविषा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहां एक ओर इब्राहीम राज्य सरकार से न्याय तथा हक की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी ओर सरकार ने न्यायालय के आदेशों के बावजूद उसकी अवहेलना करने में कोई कसर न उठा रखी।

संघर्ष कथा : चुरू जिले के गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मा इब्राहीम बचपन से ही अपनी विकलांगता से संघर्ष करता रहा। उसने घर के कोने में पड़े रहने अथवा भिखारियों जैसी दया पर निर्भर जिंदगी जीने से इनकार कर दिया। अपनी इसी जिजीविषा का परिचय देते हुए उसने १९७० में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा पास कर ली, उसके विषय थे अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र व इतिहास। बाद में उसने लोहिया कालेज चुरू से १९७४ में स्नातक तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से १९७९ में विधि स्नातक की डिग्री भी हासिल कर ली। चुरू से जयपुर आकर वह मुस्लिम मुसाफिरखाने में रहा, वहीं रह कर पढ़ता। मेधावी इब्राहीम को ब्रेल लिपि तो आती, पर उच्च शिक्षा की किताबों को साथियों से सुनकर ही याद करना पड़ता। इसी याददाश्त के सहारे तथा परीक्षा के समय सहायक लेखक की मदद से उच्च शिक्षा की सीढ़ियां सफलतापूर्वक चढ़ पाया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा १३ अक्तूबर '७९ को स्थानीय अखबारों में विज्ञापित विधि सहायक के पद के लिए इब्राहीम ने भी आवेदन किया। लिखित परीक्षा के समय इब्राहीम ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तरह ही इस परीक्षा के लिए लेखक उपलब्ध कराने की प्रार्थना की। इस पर आयोग ने उसका आवेदन रद्द करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया। यहीं से इब्राहिम का निजी जिंदगी के साथ-साथ न्यायिक संघर्ष भी शुरू हो गया।

आर्थिक रूप से कमजोर इब्राहीम ने विधिक सहायता समिति की मदद मांगी और ४ जुलाई, १९८० को उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के विरुद्ध रिट याचिका दायर कर दी। इब्राहीम के वकील के रूप में विनोद शंकर दवे व वीरेंद्र डांगी ने पैरवी करते हुए राजस्थान विकलांग अधिनियम १९७९ के तहत आरक्षित २ प्रतिशत पदों का हवाला दिया। जिसे न्यायाधीश सुरेश चंद्र

कनाडावासियों का दृढ़ विश्वास
MOODS
SKIN-THIN
LUBRICATED
3 CONDOMS
COLOURED

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम)
विश्व में सर्वाधिक कोण्डोम विनिर्माता

कौन कहता है कि केवल भारतीय
विदेशी मालों पर लट्टू हैं ?

अब कनाडावासी भी आयातित ब्रांड माँग रहे हैं ।
जैसा कि भारत में विनिर्मित कोण्डोम्स ।

फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है कि कनाडावासी के लिए
वह लट्टूपन नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास है ।

क्योंकि वे जानते हैं कि मूड्स कोण्डोम
जापान के ओकोमोटो के तकनीकी सहयोग से
विश्व में सर्वाधिक कोण्डोम विनिर्माता से
सर्वोत्कृष्ट गुणवाले लेटेक्स से बनाये जाते हैं ।

और मूड्स विश्व में अत्यन्त पतले कोण्डोमों
में गिना जाता है; उसका एहसास १००% स्वाभाविक है ।

साथ ही, ऐड्स आदि लिंग द्वारा प्रसारित
बीमारियों से अधिक संरक्षण प्रदान करता है ।

कनाडा को, लाखों मूड्स का निर्यात किया जा रहा है ।
मोज़ाम्बिक को भी लाखों मूड्स भेजे जा चुकें हैं,
यद्यपि इन देशों में संसार-भर के प्रायः सभी ब्रांडों
के कोण्डोम आसानी से मिल जाते हैं ।

और क्या आपको अब भी आयातित कोण्डोम
ज़िनकी गुणवत्ता संदेहास्पद है, माँगने में कोई झिझक नहीं होती ?

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय कोण्डोम नाम से माँगे ।
मूड्स को नाम से माँगे ।

आत्मविश्वास के साथ चलें
मूड्स को माँगे –
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के
भारतीय कोण्डोम

R K SWAMY/HLL/6662/HIN

अग्रवाल ने एक पद रिक्त रखने के निर्देश जारी कर विचारार्थ स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात तीन साल तक न्यायालय, आयोग तथा राज्य सरकार की जद्दोजहद के बाद अंततः १८ फरवरी, १९८३ को तत्कालीन न्यायाधीश गुमान मंल लोढ़ा ने इब्राहीम के पक्ष में फैसला सुना दिया।

ऐतिहासिक फैसला: इस फैसले को अंधे प्रार्थी के प्रति राज्य सरकार के अंधे रवैये के खिलाफ न्यायालय का अंधा न्याय करार देते हुए न्यायाधीश लोढ़ा ने कहा यह कोई दान अथवा दया नहीं है, बल्कि सरकार का नैतिक व संवैधानिक दायित्व है कि वह विकलांगों को भी रोजगार उपलब्ध कराये। उन्होंने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि इस अति आधुनिक वैज्ञानिक व कुछ घंटों में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले युग में भी नौकरशाही के कारण दो प्रतिशत आरक्षण के बावजूद तीन साल तक एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकी।

उन्होंने टिप्पणी करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में लिखा कि शारीरिक रूप से विकलांग प्रार्थी को मानसिक रूप से विकलांग प्रशासन से मदद की उम्मीद पूरी न होने पर अंततः न्यायालय की शरण में आना पड़ा है, फिर भी उसने अपनी लगन और मेहनत से विधि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसकी योग्यता को नकार कर राज्य सरकार और आयोग ने अपने अंधे होने का सबूत दिया है।

अपने २८ पृष्ठ के ऐतिहासिक फैसले में न्यायाधीश ने डा० हेलन केलर, कवि मिल्टन व सूरदास, एडवोकेट पं० मुकुट बिहारी लाल भार्गव, साधन गुप्त तथा ब्रेल की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने पूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी, तैमूर लंग, रणजीत सिंह, एडीसन, चर्चिल की विकलांगता की चर्चा करते हुए त्रिलोकी नाथ जोशी का भी जिक्र किया जिन्होंने अंधे होने के बावजूद वर्षों तक राजस्थान रेवेन्यू डिसीजन, राजस्थान ला टाइम्स तथा राजस्थान ला रिपोर्टर जैसे जर्नलों का कुशल सम्पादन किया।

न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा ने आदेश दिया कि प्रार्थी को तीन माह के अंदर विधि सहायक के पद पर नियुक्त किया जाये और अगर वह किसी कारण से इस पद के लिए उपयुक्त न हो, तो उसे अन्य पद पर नियुक्ति दी जाये।

अवमानना: न्यायालय के फैसले के बावजूद छह माह तक कोई कार्यवाही न होने पर इब्राहीम ने न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर कर दी। इस पर २५ अगस्त, १९८३ को तत्कालीन मुख्य सचिव एमएमके वली से जवाब तलब किया गया। जिसके जवाब में सरकार ने एक माह में नौकरी देने का आश्वासन दिया तथा इब्राहीम को विधि सहायक के बजाय तृतीय श्रेणी अध्यापक नियुक्त कर दिया। परंतु सरकार को इस पर संतोष नहीं हुआ तथा ३० दिन की मियाद समाप्त हो जाने के बावजूद २०० दिन बाद खण्डपीठ में गुमानमल लोढ़ा के निर्णय के खिलाफ झूठा शपथ-पत्र भर कर विशेष अपील कर दी। परंतु शपथ-पत्र झूठा सिद्ध होने के कारण यह अपील वापस लेनी पड़ी।

> अंततः आठ वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इब्राहीम खां ने अपना अधिकार पा ही लिया। उसने ६ दिसंबर, १९८८ को जोधपुर में जाकर नयी नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार अभी अपने लापरवाह व अड़ियल रवैये को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी ज्वाइन करने के दो माह के बावजूद न्यायालय के आदेशों को ताक पर रखकर ५ फरवरी, १९८९ तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

इधर सरकार ने इब्राहीम को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति देते समय उस पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए दो वर्ष में बीएड की डिग्री हासिल करने की शर्त लगा दी। विधि सहायक के ६६० रुपए प्रतिमाह के मुकाबले मात्र ३५५ रुपए प्रतिमाह के वेतनमान में ही संतोष कर लेने के बावजूद इब्राहीम को पहला झटका तब लगा, जब राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों ने नेत्रहीन इब्राहीम को बीएड कालेज में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। हारकर इब्राहीम को दुबारा उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

१५ जनवरी, १९८८ को वीरेंद्र डांगी ने इब्राहीम खां की ओर से एक याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय से यह स्पष्ट करने की अपील की गयी कि वह १९८३ में दिये गये फैसले में उल्लिखित 'अन्य पद' का आशय स्पष्ट करें। क्या तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद विधि सहायक के समकक्ष है, जबकि इस पद पर वेतन वृद्धि पाने के लिए बीएड करना अनिवार्य है और राज्य में नेत्रहीन प्रार्थी को बीएड में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ।

२ फरवरी, १९८८ को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुमानमल लोढ़ा तथा न्यायाधीश पानाचंद्र जैन ने नेत्रहीन शिक्षक की वेतनवृद्धि के लिए बीएड की डिग्री हासिल करने की शर्त को असंवैधानिक करार दिया तथा तीन माह के अंदर इब्राहीम खां को विधि सहायक या समकक्ष पद पर नियुक्ति देने तथा १८ फरवरी, १९८३ से वेतन की बकाया राशि का भुगतान करने के आदेश दे दिये।

परंतु इब्राहीम की लड़ाई अभी भी खतम नहीं हुई, इस बार भी सरकार ने सात माह तक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर उसने दुबारा न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की दी। जिस पर न्यायाधीश सुरेंद्र नाथ भार्गव व पानाचंद्र जैन ने १४ सितंबर, १९८८ को मुख्य सचिव वीबीएल माथुर को नोटिस जारी कर दिये। इस नोटिस के जवाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता एमआई खान सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन करने का आश्वासन देकर दो माह तक पेशियां लेते रहे। अंततः ३० नवंबर, १९८८ को दोनों न्यायाधीशों ने खान के वक्तव्य व आश्वासन पर असंतोष प्रगट किया। इस पर सरकार को एक दिसंबर, १९८८ को प्रातः अदालत के समक्ष इब्राहीम को जोधपुर में वाणिज्य कर विभाग में विधि सहायक पद पर नियुक्त करने का नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना ही पड़ा।

सरकारी दावंपेंचों से चोट खाया इब्राहीम सहसा विश्वास ही नहीं कर पाया कि उसकी लड़ायी समाप्त हो गयी। इस बार उसके वकील वीरेंद्र डांगी ने नियुक्ति पत्र में लिखे अस्थायी शब्द पर आपत्ति करते हुए आशंका प्रकट की। परंतु दोनों न्यायाधीशों ने लिखित आदेश जारी करते हुए इस आशंका को निर्मूल बताया तथा सरकार को निर्देश दिये कि बकाया वेतन की राशि दो माह में चुका दी जाये अन्यथा १२ प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। साथ ही चेतावनी भी दी कि आदेशों का पालन न होने पर इसे न्यायालय की अवमानना माना जायेगा।

अंततः आठ वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इब्राहीम खां ने अपना अधिकार पा ही लिया। उसने ६ दिसंबर, १९८८ को जोधपुर में जाकर नयी नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार अभी अपने लापरवाह व अड़ियल रवैये को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी ज्वाइन करने के दो माह के बावजूद न्यायालय के आदेशों को ताक पर रखकर उसे ५ फरवरी, १९८९ तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

इस बीच इब्राहीम पर परिवार की जिम्मेदारी भी आ गयी है, उसने डेढ़ वर्ष पूर्व एक पांव से विकलांग लड़की से शादी करके घर बसा लिया तथा वह ४ माह के बच्चे का बाप भी बन चुका है। इस अनोखी और आठ वर्षों की लम्बी लड़ाई ने इब्राहीम को थकाया नहीं है, बल्कि जीत ने उसे और उत्साहित किया है, वह बकाया राशि मिलते ही सबसे पहले अपनी पत्नी के पांव का इलाज कराना चाहता है।

—धीरज कुलश्रेष्ठ

छाया: प्रताप सिंह

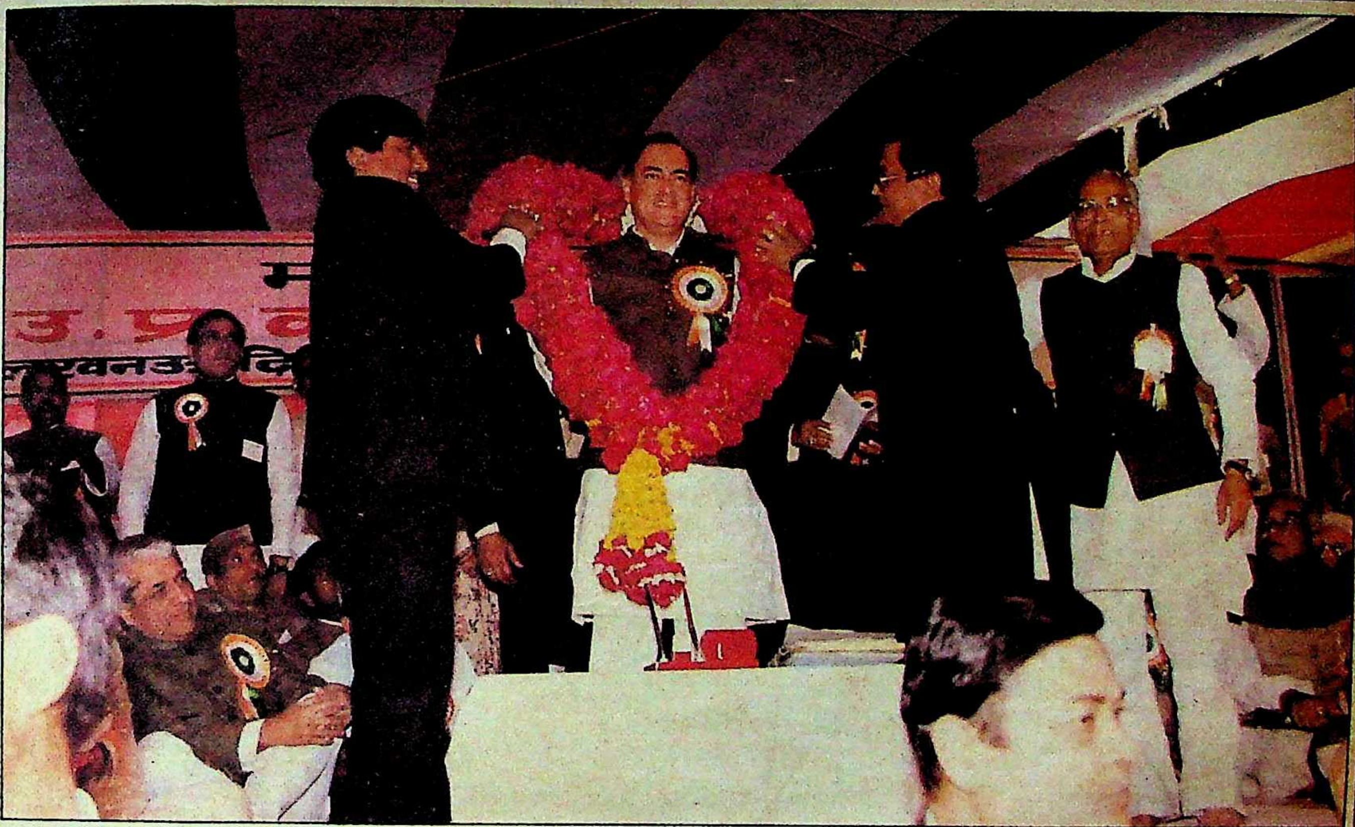

फूलों में कांटों का अहसास: सिराज मेहंदी की मदद से राजीव गांधी को सोलह किलो वजन की गुलाबी माला पहनाते बलराम सिंह यादव

छाया: मनमोहन शर्मा

इंका का महाधिवेशन

चुनावी कंधों की तलाश

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ११ वर्ष बाद लखनऊ में अपना महाधिवेशन आयोजित किया, उसमें कांग्रेसियों की भागीदारी, मनोबल और प्रतिक्रिया कैसी रही?

ग्रामपंचायतों से लेकर जिला परिषद और टाउन एरिया कमेटी से लेकर महानगर-पालिकाओं तक के चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ११ वर्ष बाद लखनऊ में अपना महाधिवेशन आयोजित किया। इसमें भाग लेने के लिए इंका समर्थक ब्लाक प्रमुखों, जिला परिषद के सदस्यों व अध्यक्षों, पालिका प्रमुखों, विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया। सेवादल के नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के नये और पुराने नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी बुलाये गये। पर कुल मिलाकर यह उखड़ते लोगों के जश्न जैसा ही था। एक निराश इंकाई का कहना है, "चरमराये ढांचे वाले सत्तारूढ़ दल को उसके अस्तित्व का अहसास कराने के लिए इस वासंती जलसे के अलावा और हो ही क्या सकता था?"

निराशाजनक उपस्थिति: १० फरवरी को लखनऊ के बेगम हजरतमहल पार्क में कांग्रेस महाधिवेशन के लिए बने पंडाल में तकरीबन दस हजार की भीड़ कांग्रेस की शक्ति का कोई शानदार प्रदर्शन नहीं थी। जिला परिषद के चुनाव, कांग्रेस ने दलीय आधार पर नहीं लड़े थे, फिर भी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बलराम सिंह यादव ने इनमें ८०.६ प्रतिशत सफलता का दावा ठोंक दिया था। प्रदेश में कुल ७४००० ग्राम पंचायतें और ८५० ब्लाक हैं, जो जिला परिषद के चुनाव की बुनियादी इकाइयां हैं। कांग्रेस ने ४७ जिलों में से ३८ पर अपने नियंत्रण का दावा किया है। एक लाख तक की आबादीवाली ६३४ टाउन एरिया समितियों और निकायों के चुनाव में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए करीब १०० उम्मीदवार अपने टिकट पर खड़े किये थे, जिनमें से २८ जीते। ५६७ कांग्रेसी इन चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, जिनमें से २४० जीते। यह एक बड़ा सबूत है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस का झंडा और पंजा अब अपना असर खो चुका है। इसी प्रकार एक लाख या इससे अधिक आबादीवाली २१ नगरपालिकाओं और छह महानगर पालिकाओं में से कांग्रेस ने ५१ प्रतिशत वोट मिलने और १५ पालिकाओं और महापालिकाओं पर अपने नियंत्रण का दावा किया। इतनी बड़ी सफलता के दावे के बावजूद इंका के महाधिवेशन में निर्वाचित कुल ग्रामप्रधानों, ब्लाक-प्रमुखों, जिला परिषद के सदस्यों व अध्यक्षों और पालिका-महापालिका अध्यक्षों में से लगभग १०-१२ प्रतिशत की ही इस महाधिवेशन में उपस्थिति, पार्टी के स्वास्थ्य के बहुत अच्छे होने की परिचायक नहीं थी।

उद्देश्य के विपरीत: प्रदेश इंका अध्यक्ष

बलराम सिंह यादव ने इस महाधिवेशन का बहुत पहले से प्रचार शुरू कर दिया था। पिछले दिनों केंद्रीय वित्तमंत्री एसबी चह्वाण ने लखनऊ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के हवाले से कहा था कि प्रदेश सरकार किसी भी समय आम चुनाव के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिस तरह राज्यों का दौरा कर रहे हैं और गरीबी, सत्ता के दलालों तथा भ्रष्टाचार को हटाने के वायदे के साथ-साथ जो कुछ बोल रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि लखनऊ का कांग्रेसी तमाशा (महाधिवेशन) प्रधानमंत्री को यह बताने के इरादे से आयोजित किया गया था कि प्रदेशाध्यक्ष बलराम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की नींव कितनी मजबूत कर दी है और पार्टी कितने जोश और खरोश के साथ चुनावी अग्निपरीक्षा के लिए तैयार है। यह महाधिवेशन इस बात का भी संकेत था कि आम चुनाव में उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी ग्रामसभा से लेकर जिला परिषद स्तर तक के पदाधिकारियों के कंधों का सहारा लेने का मन बना चुकी है।

महा अधिवेशन
कांग्रेस कमेटी
दिनांक – १० फरवरी, १९८९

सुनने के दिन लद गये: इंका कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राजीव गांधी

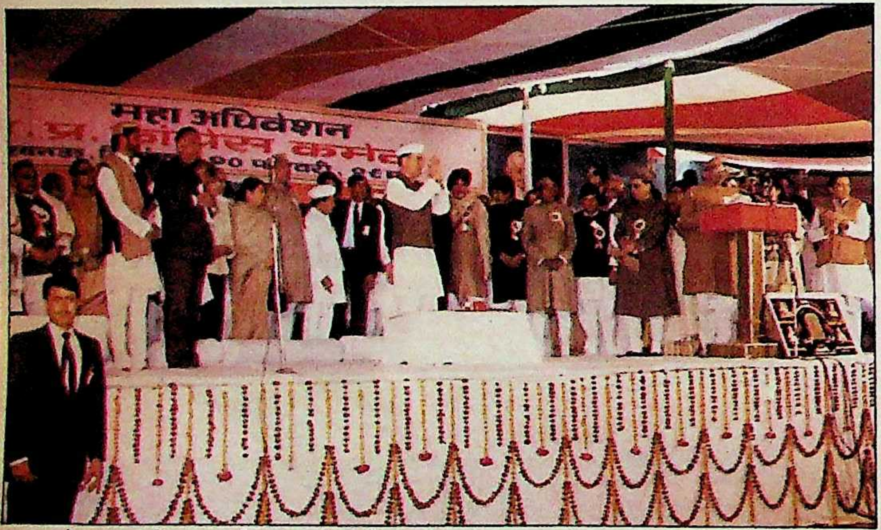

लड़खड़ाते पांव: अभिवादन स्वीकार करते राजीव गांधी

पर इस महाधिवेशन का उद्देश्य यदि सही था, तो क्या प्रदेशाध्यक्ष बलराम सिंह यादव का दूरगामी उद्देश्य पूरा होता नजर आता है? बहुत हद तक नहीं, क्योंकि 'प्रतिनिधि' के रूप में इस महाधिवेशन में आमंत्रित नवनिर्वाचित प्रमुखों और अध्यक्षों की उपस्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं रही, बल्कि पंडाल में अव्यवस्था, आपाधापी और सत्ता के नये-नये दलालों के पनपने का संकेत भी मिला। पार्टी के विभिन्न स्तरों पर मची खींचातानी का पता तो चला ही, यह शोचनीय दृश्य भी देखने को मिला कि कांग्रेसी लिबास में लिपटे कार्यकर्ताओं के कहने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी जूनियर डाक्टरों को 'मार भगाने' के लिए उन पर अंधाधुंध लाठी बरसा कर प्रदेश प्रशासन के लिए एक जबर्दस्त सिरदर्द पैदा कर दिया।

चाटुकारिता के मतलब: प्रदेश कांग्रेस-इ के इस जमावड़े में सबसे बड़ी चीज थी चाटुकारिता। मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तो अपने 'ऋतुराज' को मंच पर बैठा देख कर कोयल की तरह कुहकने और मोर की तरह नाचने लगे। अपने भाषण के दौरान एक बार तो तिवारीजी 'मेरा रंग दे बसंती चोला' वाला गाना गाकर थिरक ही उठे। चाटुकारिता की इस दौड़ में भला बलराम सिंह यादव कब पीछे रहने वाले थे? 'दिल्लीश्वरों वा जगदीश्वरों वा' के लहजे में वे गा उठे, "हमें दुनिया की ईदों से भला क्या वास्ता गालिब/हमारा चांद दिख जाये, हमारी ईद हो जाये।" इस चाटुकारिता और नाचने-गाने के दो मतलब लगाये गये—एक यह कि जनता की शक्ति और सहारे पर कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं है और दूसरा यह कि वे 'ग्रह-नक्षत्रों' के बल पर सब कुछ सध जाने के अंधविश्वास से प्रेरित और प्रभावित थे। इस होड़ में नारायण दत्त तिवारी ने बलराम सिंह यादव को निकाय चुनावों के बाद दूसरी बार पछाड़ा। दरअसल, बलराम सिंह यादव शुरू से ही नहीं चाहते थे कि पंचायतों, जिला परिषदों और नगरनिकायों तथा पालिकाओं के चुनाव कराये जायें। पर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश प्रशासन की बागडोर संभालने के साथ ही महसूस किया कि कांग्रेस के संगठन पक्ष का उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपनी सरकार और साथ ही पार्टी की भी लोकतंत्री छवि को उजागर करने के उद्देश्य से जिला परिषद और पालिकाओं के चुनाव की तारीखें निश्चित कर दीं। मुख्यमंत्री का इरादा यह भी था कि इस तरह बलराम सिंह यादव के निष्प्रभावी होने की सचाई को भी सामने ला दिया जाये।

नारायण दत्त तिवारी ने अपने फैसले से न केवल बलराम सिंह यादव को अक्षम सिद्ध किया, बल्कि वीर बहादुर सिंह की धुरी को भी कमजोर कर दिया। तिवारीजी ने कई जिलों और पालिकाओं में अपनी पसंद के व्यक्तियों को आगे बढ़ाया और जिताया, पर बलराम सिंह यादव ने अपने समर्थक वीर बहादुर सिंह को प्रसन्न करने के लिए जब जिला परिषद और निकायों के चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश की, तब पार्टी के नेताओं के आपसी मतभेद इतने उग्र हो उठे कि जिला परिषद अध्यक्षों और पालिका अध्यक्षों के टिकट बांटने के लिए पार्टी हाईकमान को करीब पांच दर्जन प्रेक्षक भेजने पड़े। इस स्थिति का पूरा लाभ तिवारीजी ने उठाया। अपने आप को पंच की स्थिति में रख कर उन्होंने सरकार और संगठन दोनों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। तिवारी ने इन चुनावों के माध्यम से कई अन्य राजनीतिक उद्देश्य

भी पूरे किये। कांग्रेस हाईकमान ने तिवारीजी की शुरू में सरकार बनाने से लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति गठित करने तक जैसी उपेक्षा की, उसका भी जवाब उन्होंने हाईकमान को दे दिया और प्रदेश की चुनावी राजनीति में अपने आपको केंद्र बिन्दु बना लिया है।

मंच की होड़ : प्रदेश कांग्रेस महाधिवेशन में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी भाषण देने पंडाल में पहुंचे, तब प्रदेश के मंत्रियों में अपने 'चांद' के इर्दगिर्द तारे की भांति दिखायी देने की अजीब होड़ देखने में आयी। सभी मंच पर राजीव गांधी के साथ बैठना चाहते थे, पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जगदंबिका पाल और नरेशचंद्र को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जगदंबिका पाल को इसलिए कि वे गुलाम नबी आजाद के 'प्रिय' हैं और नरेशचंद्र को इसलिए कि वे घुसकर तमाशा देखने की कला में निपुण हैं। वैसे राज्यमंत्री गौरीशंकर भी इस कला में माहिर हैं, पर उनको पंडाल में दरी पर बैठना पड़ा। लोकपति त्रिपाठी, गोपीनाथ दीक्षित, श्यामसूरत उपाध्याय, बलदेव सिंह आर्य, नरेंद्र सिंह आदि वरिष्ठ मंत्रियों को मंच से बहुत दूर पंडाल के एक कोने में जमीन पर बैठना पड़ा। पंडाल में आते समय उन्हें 'मेटल डिटेक्टर' से गुजरना पड़ा। मंच पर कब्जा करने या मंच से दूर एक कोने में ब्रिठाये जाने की यह घटना चाहे आकस्मिक रही हो, पर जो इसका राजनीतिक मतलब लगाना चाहते हैं और इसे मंच पर बैठे 'जूनियर' मंत्रियों द्वारा 'सीनियर' मंत्रियों को उनकी असलियत का अहसास कराने की कार्रवाई कहते है, उन्हें रोका भी कैसे जा सकता है? शायद यही वजह थी कि दूर एक कोने में बैठे लोकपति त्रिपाठी को, मंच पर खड़े जगदंबिका पाल को जोर से आवाज देनी पड़ी, "पाल साहब, जरा किनारे हट जायें, हम सीनियर मंत्री अपने 'चांद' (प्रधानमंत्री) का दर्शन करना चाहते हैं।"

सपनों के ताजमहल को खतरा : सत्तर हजार रुपए की लागत से बने ताजमहल को लेते हुए राजीव गांधी

कांग्रेस हलकों में इस बात को लेकर भी काफी रोष है कि कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आजाद ने पंडाल में बैठे कार्यकर्ताओं और निर्वाचित अध्यक्षों को राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने पर उन्हें डांटा, "चुप रहो!" प्रधानमंत्री सहित कुछ पुराने कांग्रेसी इस 'डांट' से सकपका गये। इस पर आजाद ने सफायी देते हुए ऊंची आवाज में कहा, "उत्तर प्रदेश के लोग इसी तरह की भाषा समझते हैं। यहां के लोग ऐसी भाषा सुनने के आदी हैं।" तमाम इंकाई यह उम्मीद लगाये हुए थे कि प्रधानमंत्री की सुनने के बाद उन्हें अपनी सुनाने का कुछ मौका भी मिलेगा। पर प्रधानमंत्री तो व्यस्त थे ही, उनके साथ दिल्ली से आये कार्यकर्ताओं के पास भी प्रधानों, प्रमुखों, अध्यक्षों आदि की बात सुनने का समय नहीं था।

इस महाधिवेशन की तर्ज और ताल यही थी कि जो प्रधान और अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, आने वाले आम चुनाव में उन्हीं से कांग्रेस के हरावल दस्ते बनेंगे। कांग्रेस आगामी आमचुनाव की तैयारी नियोजित ढंग से कर रही है, यह बात भी इस महाधिवेशन से स्पष्ट हो गयी है। इसी के साथ यह भी साफ हो गया है कि निकट भविष्य में साफ सुथरा राजनीतिक माहौल बनाने के नाम पर कुछ मंत्रियों और दिग्गज कांग्रेसियों पर गाज गिरने वाली है।

अग्नि-परीक्षा : शुरू में यह तय किया गया कि बड़े पैमाने पर १९८८ के बाद आयोजित इस सम्मेलन में सिर्फ विधायकों, सांसदों और पार्टी के प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों को ही बुलाया जायेगा, बाद में जब दिल्ली से निर्देश आया कि अधिवेशन में जिला परिषद अध्यक्षों, ब्लाक-प्रमुखों, सभासदों तथा ग्रामप्रधानों को भी शामिल करना जरूरी है, तब कार्यक्रम का स्वरूप ही बदल गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद से बलराम सिंह यादव भी केंद्रीय हाईकमान को अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। महासम्मेलन के नाम पर उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता नजर आने लगा। बस फिर क्या था। बलराम सिंह यादव ने अपने 'प्रियपात्र' संयुक्त सचिव सिराज मेहंदी को व्यवस्था समिति का मुख्य कर्ताधर्ता बना दिया। हर जिले में मंत्रियों और प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों को भीड़ जुटाने के लिए लगा दिया गया। इतना ही नहीं ४ फरवरी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और बलराम सिंह यादव ने मंत्रियों, जिला परिषद अध्यक्षों तथा जिला कांग्रेस-अध्यक्षों की बैठक भी की, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं में फैला असंतोष प्रधानमंत्री के सामने जाहिर न हो सके। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि महाधिवेशन में भाग लेनेवाले मंत्रियों और निगमों के अध्यक्षों से १०० रुपए, सांसदों, विधायकों, जिला परिषदों तथा सहकारी बैंकों के अध्यक्षों से ५० रुपए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश, जिला व ब्लाक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से २५ रुपए और अन्य सभी प्रतिनिधियों से ५ रुपए प्रतिनिधि शुल्क के रूप में लिये जायें। बाद में कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण यह निर्णय ऐन मौके पर रद्द करना पड़ा।

बलराम सिंह यादव के लिए इस महासम्मेलन की सफलता अग्नि-परीक्षा की तरह थी। क्योंकि प्रदेश इंका अध्यक्ष बनने के बाद उनकी अध्यक्षता में होनेवाला यह पहला सम्मेलन था। शायद यही वजह थी कि महासम्मेलन की सफलता की खबरें बढ़ा-चढ़ा कर छापने के उद्देश्य से ही उन्होंने महासम्मेलन से दो दिन पूर्व तमाम पत्रकारों को अपने आवास पर बुला कर न केवल दावत दी, वरन उन्हें कीमती 'उपहार' भी दिये।

महाधिवेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को प्रातः दस बजे करना था, किंतु दिल्ली में प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण एक दिन पूर्व यह समय बदल कर प्रातः ८ बजे कर दिया गया। प्रधानमंत्री के साथ अधिवेशन में भाग लेने के लिए दिल्ली से वीर बहादुर सिंह, केसी पंत, दिनेश सिंह, शीला दीक्षित, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, महावीर प्रसाद, शीला कौल, बीएन गाडगिल, मनोरंजन तथा केदारनाथ सिंह भी आये थे, लेकिन महाधिवेशन में प्रधानमंत्री के बाद सबसे अधिक महत्व मिला गुलाम नबी आजाद को। ऐसा शायद इसलिए किया गया था क्योंकि आजाद, उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी भी हैं।

पंडाल का नजारा : प्रधानमंत्री को अमौसी हवाई अड्डे से अधिवेशन स्थल (बेगम हजरतमहल पार्क) तक कार से आना था, लेकिन स्कूटर इंडिया कारखाने को निजी क्षेत्र में बेचने के सरकारी निर्णय के विरोध में कारखाने के कर्मचारियों ने हवाई अड्डे से लेकर बेगम हजरतमहल पार्क के बीच में रास्ता जाम करने की जब धमकी दे दी, तो प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे से हेलीकाप्टर द्वारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लाया गया, जहां से वे पास में ही स्थित अधिवेशन स्थल पर पहुंचे। पहले की तरह इस बार

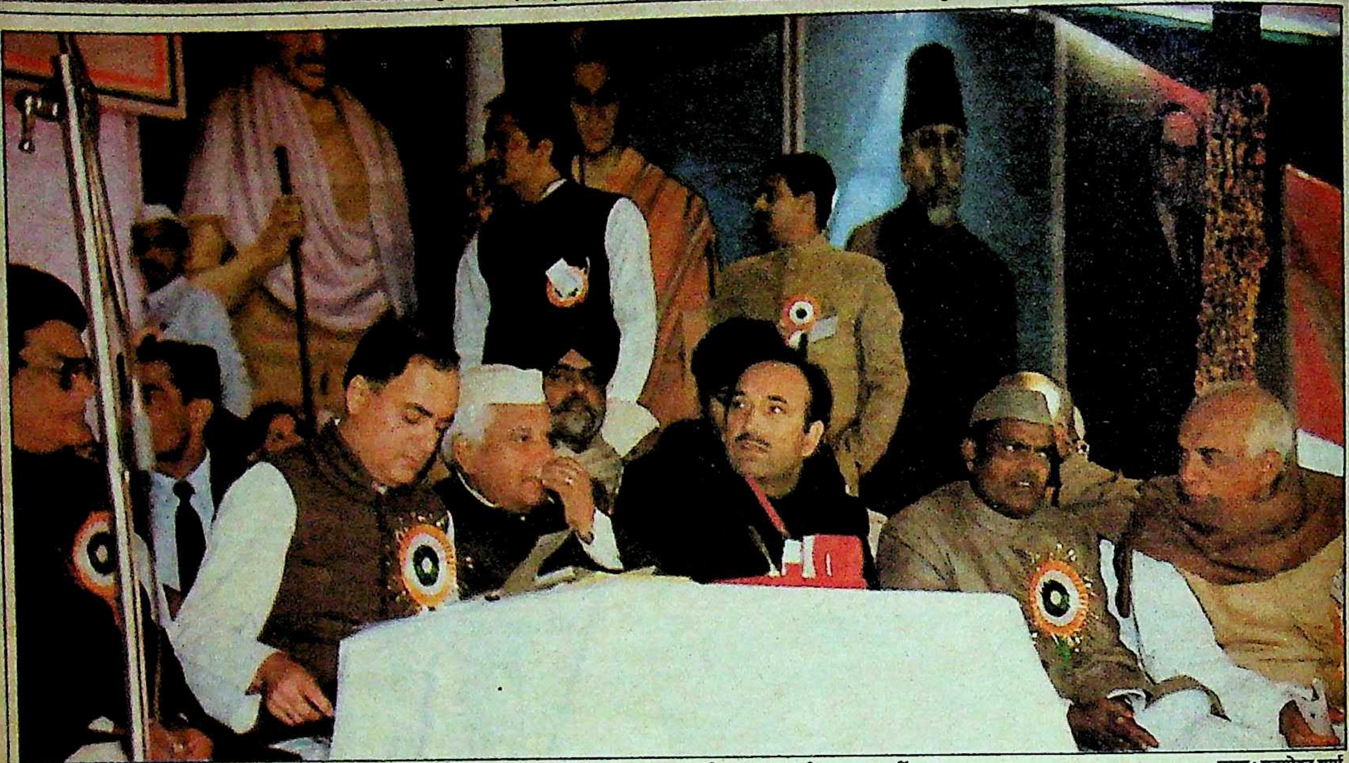

परस्पर विरोधी नजरें : महाधिवेशन मंच पर राजीव गांधी, नारायण दत्त तिवारी, गुलाम नबी आजाद, वीर बहादुर सिंह

छाया : मनमोहन शर्मा

भी प्रधानमंत्री अपने साथ दिल्ली से पत्रकारों और दूरदर्शन की एक बड़ी टीम लेकर आये थे। मुश्किल से दस हजार लोगों की मौजूदगीवाले पंडाल का नजारा देखकर ऐसा लगता था कि यह महाधिवेशन कांग्रेस पार्टी का न होकर एक स्थानीय मांटेशरी स्कूल का वार्षिकोत्सव सा था। क्योंकि उक्त स्कूल द्वारा २६ जनवरी की परेड के अवसर पर निकाली गयी भव्य झांकी, पंडाल में महत्वपूर्ण स्थान पर रखी गयी थी। स्कूल की अध्यापिकायें और सैकड़ों की संख्या में छात्र 'स्वागत गान' के लिए पंडाल में मौजूद थे।

कई प्रमुख कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बलराम सिंह यादव, कुछ 'निजी कारणों' की वजह से इस स्कूल को महत्व दे रहे थे। महाधिवेशन में किसी निजी स्कूल की दखलंदाजी, प्रधानमंत्री को भी काफी अखरी, क्योंकि दो घंटे के प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में ४५ मिनट से अधिक का समय (एक स्वागत गान बीच में ही रोक लिये जाने के बावजूद) इस स्कूल को ही दे दिया गया था।

इस महा सम्मेलन में प्रदेश इंका के किसी भी उप संगठन या इकाई की कोई भागीदारी नहीं थी। कुछ महीनों पूर्व तक संगठन में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे, 'सेवादल' की सेवा भावना भी इस अवसर पर नहीं दिखायी पड़ी। शायद यही वजह थी सेवादल के प्रदेश प्रमुख के पद पर रह चुके जगदंबिका पाल को मंच से यह कहना पड़ा, "अब मैं सेवादल से सरकार में आ गया हूं, इसलिए सेवादल के लोग मेरा 'आदेश' नहीं मान रहे हैं।"

प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मात्र तीन लोगों, बलराम सिंह यादव, नारायण दत्त तिवारी और गुलाम नबी आजाद के भाषण हुए। बलराम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री के सम्मान में जो अभिनंदनपत्र पढ़ा, उसमें संगठन की बात कम, राजीव की 'चरण वंदना' अधिक थी। यह अभिनंदन-लेख पांच फिट लंबे डेढ़ फिट चौड़े ताम्रपत्र पर खुदा हुआ था। बलराम सिंह यादव ने सिराज मेहंदी की सहायता से प्रधानमंत्री को सोलह किलो वजन की गुलाबी माला पहनायी। साथ ही ७० हजार रुपए की लागत से बने ताजमहल का एक छोटा माडल भी प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। यह माडल आगरे के एक बड़े व्यापारी की कृपा से सिराज मेहंदी को मिला था।

सिराज मेहंदी द्वारा की गयी इन 'व्यवस्थाओं' का 'पुरस्कार' भी उन्हें उसी दिन मिल गया। वीर बहादुर के कड़े विरोध के बावजूद बलराम सिंह यादव ने सिराज मेहंदी को प्रदेश इंका के 'काडर (कैडर) बिल्डर सेल' का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि इंका के सभी इकाइयों के प्रशिक्षण शिविर 'काडर बिल्डर सेल' के अध्यक्ष की देखरेख में ही लगेंगे।

छवि का निखार: महाधिवेशन में राजीव गांधी ने जिस तरह का भाषण दिया, वह विरोधी दल के किसी नेता के भाषण से भी तीखा था। मसलन, "पंचायती राज को किसी भी कीमत पर मजबूत करना है। दिल्ली में बैठकर गांवों का राज नहीं चल सकता। आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। हमारे पास शिकायत आती है। हम मुख्यमंत्री को जांच के लिए भेज देते हैं। मुख्यमंत्री उस शिकायत को संबंधित मंत्री के पास भेज देता है। मंत्री, सचिव की तरफ उसे सरका देता है। सचिव और नीचे भेज देता है। होते-होते यह एक पुलिंदा बन जाता है और जांच उसी के पास पहुंच जाती है जिसके खिलाफ शिकायत होती है। ऊपर तक जब जांच रिपोर्ट पहुंचती है, तो एक ही मसले की फाइल इतनी मोटी हो जाती है कि उस पर कार्रवाई करना ही मुमकिन नहीं रहता।" इसी प्रकार, "ऊपर का भ्रष्टाचार हमने कुछ कम किया है, लेकिन नीचे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर भी हमारे अलावा किसी ने भी भ्रष्टाचार को मिटाने का काम नहीं किया। हमें पता चला कि एक गवर्नर अपनी बेटी के लिए कुछ कर रहे थे। हमने कहा आप हट जाइये। एक मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, हमने हटा दिया। दूसरे मुख्यमंत्री का मामला आया, हमने उनसे भी इस्तीफा ले लिया। विपक्ष में तो अनेक नेताओं के खिलाफ कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन हटा कोई? दिया किसी ने इस्तीफा?"

राजीव गांधी ने कांग्रेसी दिग्गजों के भ्रष्टाचार का जिक्र पहली बार किया है। इसका मतलब यह लगाया जा रहा है कि आनेवाले दिनों में इस प्रचार को लगातार तेज किया जानेवाला है कि अगर जरूरी हुआ, तो दो-चार और लोग भी इस छविनिर्माण में बलि चढ़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पूर्व राजीव गांधी एक बार फिर अपने लिये 'मिस्टर क्लीन' का सम्बोधन सुनने को उत्सुक हैं।

—अजय कुमार

Digitized by [illegible] and eGangotri

सांखनी

पुलिस की मौजूदगी में भीषण नरसंहार

उन्होंने लिखित रूप से पुलिस-सुरक्षा की मांग की थी, फिर भी बुलंदशहर के सांखनी गांव में ११ लोग मौत के घाट कैसे उतर गये?

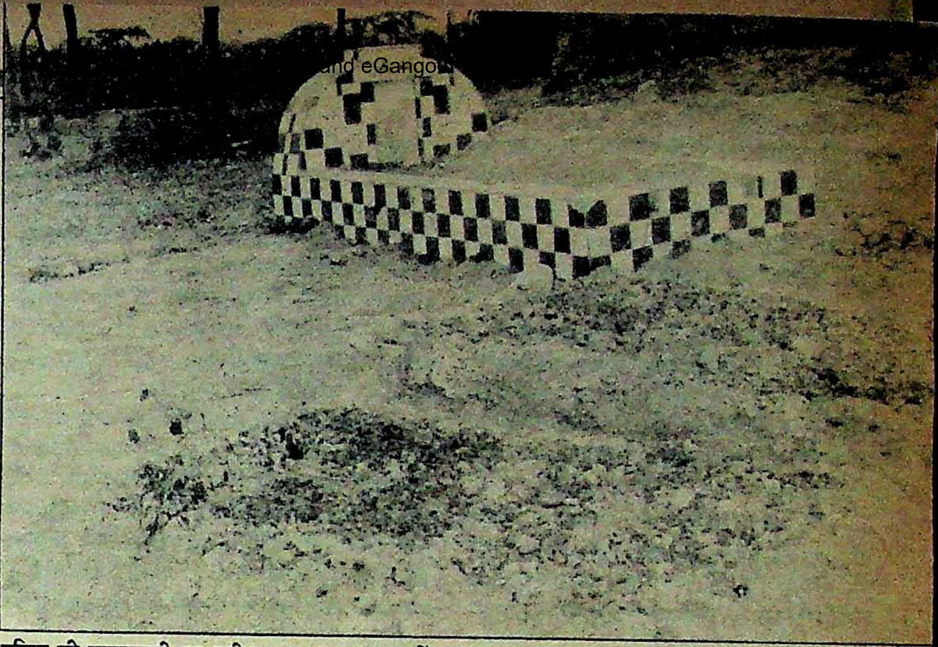

पुलिस की लापरवाही का नतीजा: एक साथ दस कब्रें

उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल इन दिनों प्रतिशोध की आग में जल रहा है। दंगे की त्रासदी से उबरने के बाद अब यहां सामूहिक नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया है। गत दो मास में सामूहिक हत्याकांड की लगभग आधा दर्जन घटनाओं ने इस मंडल को चंबल और बुंदेलखंड की श्रेणी में ला खड़ा किया है। विडम्बना यह है कि इन हत्याओं के पीछे आपसी रंजिश तो है ही, राजनेताओं की रहनुमाई तथा पुलिस की शह व लापरवाही भी प्रमुख कारण है। इसी पहली फरवरी को बुलंदशहर के सांखनी गांव में हुआ ११ लोगों का सामूहिक नरसंहार भी इन्हीं कारणों का दुष्परिणाम था।

उस दिन सांखनी गांव का कब्रिस्तान रणक्षेत्र बन गया था। चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। पूरे कब्रिस्तान में हमलावरों के ललकारने और मारे जानेवालों की दिल दहला देनेवाली चीख-पुकार गूंज रही थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी हमलावरों से टक्कर लेने के बजाय इधर-उधर जा छिपे थे। लगभग एक घंटे के खूनी तांडव के बाद, हमलावर जिस दबंगई से आये थे, वैसे ही बेखौफ वहां से चले गये।

रंजिश की पृष्ठभूमि: बुलंदशहर से ३५ किलोमीटर दूर जहांगीराबाद-अहार मार्ग पर स्थित अभागे गांव सांखनी की कुल आबादी नौ हजार है। इसमें लगभग आठ हजार शिया मुसलमान तथा बाकी अन्य सम्प्रदाय के लोग हैं। गांव में सर्वाधिक सम्पन्न दो परिवार हैं—पहला ग्रामप्रधान शमशुल का और दूसरा मुहम्मद अली का परिवार। क्रमशः तीन सौ और ढाई सौ बीघा जमीन के स्वामी इन दोनों परिवारों के बीच वर्षों पुरानी रंजिश है। रंजिश का कारण क्या था? इस बारे में मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीराम अरुण कहते हैं, "इसके पीछे गांव में सात वर्ष पूर्व हुआ ग्रामप्रधानी का चुनाव था।" जबकि वास्तव में आठ वर्ष पूर्व दोनों गुटों में दुश्मनी तब ठनी, जब मुहम्मद अली के परिवार की एक लड़की को शमशुल के परिवार ने तलाक दे दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए मुहम्मद अली तथा उसके लड़के मुहम्मद हुसैन ने २० मार्च, १९८१ को शमशुल के भाई बदर की हत्या कर दी। इस अपराध में मुहम्मद अली सहित उसके परिवार के १२ लोगों को २६ अप्रैल, १९८२ को उच्च न्यायालय ने आजन्म कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में जमानत पर छूटकर मुहम्मद अली अपने परिवार के साथ दिल्ली में बस गया, क्योंकि उसे भय था कि गांव में रहने पर शमशुल अपने भाई की हत्या का बदला जरूर लेगा।

घटनाक्रम: मुहम्मद अली और शमशुल दोनों ही शिया मुसलमान हैं। इस गांव की परम्परा है कि शिया संप्रदाय के लड़के-लड़कियों का विवाह गांव के ही निवासी से होता है। इसी प्रकार गांव के किसी निवासी की मृत्यु चाहे कहीं भी हो, उसे दफनाया गांव के कब्रिस्तान में ही जाता है। यही परम्परा मौत का पैगाम बनकर मुहम्मद अली तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को दिल्ली से सांखनी खींच लायी। दरअसल, इसी ३१ जनवरी को मुहम्मद अली के पुत्र मुहम्मद हुसैन की सास फरमूदन बेगम की दिल्ली में मृत्यु हो गयी थी। मरने से पूर्व फरमूदन ने दामाद मुहस्मद हुसैन से कहा था, "मुझे गांव के कब्रिस्तान में ही दफन करना। इसके लिए चाहे तुम्हें शमशुल से टक्कर ही क्यों न लेनी पड़े...यह मेरी आखिरी इच्छा है।"

फरमूदन बेगम की इच्छा पूरी करने के लिए उसका शव लेकर मुहम्मद अली पहली फरवरी को दिल्ली से बुलंदशहर आया। चूंकि मुहम्मद अली को यकीन था कि सांखनी में कदम रखते ही शमशुल की ओर से हमला हो सकता है, इसलिए उसने बुलंदशहर के अकबरपुर, दरियापुर, चंदेरा तथा कमलापुर गांव के लगभग २५ हथियारबंद लोगों को भी साथ ले लिया। खूनखराबे से आशंकित मुहम्मद अली ने जहांगीराबाद थाने में अर्जी देकर शव दफनाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। खानापूरी करने के लिए थाना प्रभारी सत्यवीर चौहान ने केवल एक उपनिरीक्षक सुदर्शन चंद्र कटौच तथा दो सिपाही श्याम वीर व रमेश कुमार के साथ उन लोगों को गांव भेज दिया।

उपनिरीक्षक कटौंच बताते हैं, "पुलिस तथा हथियारबंद लोगों के साथ मुहम्मद अली को गांव में आया देख शमशुल आग बबूला हो उठा था। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मुहम्मद अली किसी शव को दफन करने आया है, तो वे शांत हो गया। उसने मुझसे कहा कि आप इन लोगों से कह दें कि शव दफनाकर फौरन वापस लौट जायें। उसके बाद मैं इन्हें एक मिनट भी गांव में देखना नहीं चाहता।"

घटना का प्रत्यक्षदर्शी नजाकत अली बतांता है, "दोपहर दो बजे का वक्त था। फरमूदन बेगम की लाश को कब्र में लिटाया जा चुका था। मुहम्मद अली तथा उसके परिवार के लोग कब्र में मिट्टी डाल रहे थे। तभी गांव की ओर से घोड़ों पर सवार होकर शमशुल तथा उसका भाई रसीदुल जफर वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में राइफलें थी। उनके पीछे-पीछे तलवार, बल्लम और बंदूकें लिये ११-१२ लोग और भी थे। शमशुल ने दरोगा कटौच से कहा कि लाश दफन हो चुकी है। अब इन लोगों को यहीं से वापस कर दो, वरना पचासों लोग मारे जायेंगे।

उपनिरीक्षक कटौंच के अनुसार, "उस वक्त मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मौके की गंभीरता को देख मैंने फोर्स मंगाने के लिए एक व्यक्ति को थाने रवाना किया। मुहम्मद अली तथा उसके साथ शव को दफनाने आये लोगों को समझाया कि शमशुल प्रधान ठीक कहते हैं...अब आप लोग दिल्ली लौट जायें। लेकिन मुहम्मद अली चीख-चीखकर कह रहा था कि हम किसी से कम नहीं। हम तीन दिन तक गांव में ही रहकर 'सपरा' (मातम) मनायेंगे।"

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, "अभी यह तकरार शुरू ही हुई थी कि मुहम्मद अली के किसी साथी ने हवाई फायर कर दिया। इसके बाद तो शमशुल ने किसी को कुछ सोचने-समझने का मौका ही नहीं दिया। उसने तथा उसके साथियों ने उस

स्थान को चारों तरफ से घेर लिया, जहां शव को दफनाने आये मुहम्मद अली और लगभग ५० लोग खड़े थे। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गयी। तब तक थाने से दरोगा और छह सिपाही और आ चुके थे। गोलियां चलती देख ये सब एक खेत में छुप गये।''

फायरिंग शुरू होते ही मुहम्मद अली के साथ आये अन्य गांवों के हथियारबंद लोग शमशुल के आगे गिड़गिड़ाने लगे। शमशुल ने उन लोगों के हथियार छीनकर उन्हें भाग जाने को कहा। लेकिन उसने मुहम्मद अली तथा उसके परिवार के लोगों को नहीं बख्शा।

मारे गये दस लोग एक ही परिवार के थे। इनमें मुहम्मद अली, उसके भाई शौकत अली असगर आबिद, रिश्तेदार फराकत हुसैन —इमदाद (बाप-बेटे), साबिर मुनव्वर, कल्लू बेग—मुनव्वर हुसैन (बाप-बेटे) तथा आजाद हुसैन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। ग्यारहवां मृतक रजी हसन, शमशुल के गुट का व्यक्ति था जिसे पुलिस अपनी गोली से मारा गया बताती है। इसके अलावा डेढ़ दर्जन से भी अधिक लोग घायल हुए। हालांकि पुलिस रिकार्ड में इन घायलों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है।

हमलावरों की गोलियों से संयोग से बचे मुहम्मद अली के इकलौते पुत्र मुहम्मद हुसैन का कहना है, ''मैंने एक पेड़ की आड़ लेकर जान बचायी। शमशुल और उसके साथी हमारे खानदान के लोगों को मौत के घाट उतारते रहे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने हमलावरों पर एक गोली तक नहीं चलायी। दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ढिल्लों का कहना है, ''पुलिस ने घटनास्थल पर ४ चक्र गोलियां चलायीं। रजी हसन को पुलिस की ही गोली लगी है।''

घटना के बाद : बहरहाल, इस घटना के बाद पूरे गांव में मौत का सन्नाटा छा गया। गांव के अधिसंख्य पुरुष घर से भाग गये। औरतें और बच्चे घरों की किवाड़ों के पीछे कैद हो गये। हादसे की खबर मिलते ही जिले के आला अफसरों में हड़कम्प मच गया। बचाव की दृष्टि से जहांगीराबाद थाने के प्रभारी सत्यवीर चौहान ने थाने के रोजनामचे में तो बुलंदशहर की रवानगी दर्ज की, लेकिन वहां न जाकर अपने क्वार्टर चले गये। उधर पुलिस लाइन में खुर्जा जाने के लिए तैयार खड़ी पीएसी की एक प्लाटून को फौरन सांखनी रवाना कर दिया गया। लगभग तीन घंटे बाद सांखनी गांव पुलिस की छावनी बन गया था।

पुलिस की लापरवाही : इस मामले में पुलिस की लापरवाही के तमाम ऐसे पारदर्शी पहलू हैं, जिनसे पुलिस की निष्क्रियता साफ झलकती है। जो व्यक्ति गोलीकांड में मारे गये, उन्होंने घटना से पूर्व ही खूनखराबे की आशंका व्यक्त की थी। लेकिन उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके साथ केवल तीन पुलिसकर्मी भेजे गये। घटनास्थल पर ऐन वक्त पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी साइकिल से रवाना किया गया, जबकि थाने में जीप मौजूद थी। थाने से घटनास्थल की दूरी सात किलोमीटर है। बाद में भेजी गयी फोर्स यदि वक्त पर पहुंच जाती, तो यह हादसा टल सकता था।

जिस वक्त जिले में इतनी बडी वारदात हुई, उस वक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहर से गायब थे। प्रदेश के श्रममंत्री सईदुल हसन उस वक्त नरौरा क्षेत्र में एक हड़ताल तुड़वा रहे थे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ढिल्लों भी उनके आगे-पीछे लगे हुए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दयाशंकर सिंह मेरठ गये हुए थे और परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीराम अरुण भी न मालूम कहां थे? यही कारण था कि जिला स्तर के पुलिस अधिकारी घटना के तीन घंटे बाद मौके पर पहुंचे। हालांकि श्रममंत्री सईदुल हसन इसी जिले के निवासी हैं, लेकिन घटना की

पहले थोड़े ही पता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जायेगी। हमलावरों की प्लानिंग का पुलिस को कुछ पता नहीं था।

साक्षात्कार/श्रीराम अरुण
पुलिस उपमहानिरीक्षक

'यह घटना इतनी बड़ी नहीं'

माया: ***जिस दिन सांखनी में इतनी बड़ी वारदात हुई, उस दिन पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी शहर में मौजूद नहीं था। आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि आप उस दिन दिल्ली में थे?***

श्रीराम: *नहीं, मैं तो मेरठ में ही था। वैसे, यह इतनी बड़ी घटना नहीं, जितना लोग समझ रहे हैं। यह पारिवारिक रंजिश का मामला है।*

माया: ***आप घटनास्थल पर कब पहुंचे?***

श्रीराम: *अगले दिन, २ फरवरी को।*

माया: ***मृतकों ने फरमूदन बेगम के शव को दफनाने के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। पुलिस को अपनी पारिवारिक रंजिश का इतिहास बताने के साथ उन लोगों ने किसी अनहोनी की भी संभावना व्यक्त की थी। फिर भी सुरक्षा के नाम पर उन्हें केवल एक दरोगा और दो सिपाही दिये गये?***

श्रीराम: *पहले थोड़े ही पता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जायेगी। हमलावरों की प्लानिंग का पुलिस को कुछ पता नहीं था। गनीमत तो यह रही कि अभियुक्तों ने अचानक हमला किया, वरना मरनेवालों की संख्या ५० भी हो सकती थी।*

माया: ***इस बात को थोड़ा स्पष्ट कीजिए।***

श्रीराम: *दरअसल, जो व्यक्ति मरे, वे भी पूरी तैयारी से आये थे। उनके पास भी कट्टे-तमंचे थे। लेकिन अचानक हमला होने से उन्हें जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं मिला।*

माया: ***आपको कैसे पता चला कि मृतकों के पास 'अवैध असलहा' था? क्या पुलिस को घटनास्थल या मृतकों के पास से कोई हथियार मिला? या फिर मुहम्मद अली गुट के लोगों के साथ गयी पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि उनके पास अवैध असलहा है।***

श्रीराम: *पुलिस को यह जानकारी काफी बाद में हुई। जहां तक घटनास्थल से असलहा बरामद होने की बात है, तो वह भी नहीं हुआ, क्योंकि घटना के बाद अभियुक्त मृतकों का असलहा भी साथ ले गये।*

माया: ***घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ने क्या किया?***

श्रीराम: *पुलिस ने चार चक्र गोलियां चलायीं, जिससे एक अभियुक्त रजी हसन मारा गया।*

माया: ***लेकिन बुलंदशहर में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो उसके शरीर पर किसी धारदार हथियार के घाव बताये गये हैं।***

श्रीराम: *यह बात ठीक है, लेकिन ४ फरवरी को हमने उसका मेरठ में दोबारा पोस्टमार्टम कराया था। इस बार की रिपोर्ट के अनुसार, रजी हसन के शरीर पर 'गनशट' के घाव पाये गये हैं।*

माया: ***दोबारा पोस्टमार्टम की वजह? क्या किसी को पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर शक था?***

श्रीराम: *नहीं, यह हमने अपनी संतुष्टि के लिए कराया।*

—रा०स०

सूचना पाकर घटनास्थल पर जाने के बजाय, नरौरा से ही वे तत्काल बरेली निकल लिये।

गांव के लोग बताते हैं कि घटना के दो घंटे बाद तक शमशुल तथा उसके साथी गांव में ही थे। लेकिन उस दौरान पुलिस ने गांव में घुसने की हिम्मत नहीं की। यही कारण था कि १५ लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद पुलिस केवल पांच लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी। मुख्य अभियुक्त शमशुल तथा अन्य अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

लीपापोती: पुलिस ने अपने बचाव की शुरुआत प्राथमिकी से ही कर दी थी। चर्चा है कि केवल १५ मिनट में लिखी गयी ३ पेज (लगभग ७०० शब्द) की प्राथमिकी में पुलिस के प्रति शुक्रगुजारी दर्शाते हुए यह भी कहा गया है, "मौके पर यदि पुलिस न होती, तो ५०-६० मारे जाते।" दरअसल, यह प्राथमिकी घटना के अगले दिन पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा काफी सोच-विचार के बाद दर्ज हुई थी। तब तक जहांगीराबाद थाने के रोजनामचे मे इंदराज रोक दिया गया था।

सवाल है कि जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने क्या किया? उन पुसिलकर्मियों का कहना है, "हमने कोई गोली नही चलायी। साहब, हमारी तो दोनों तरफ से मुसीबत है। गोली नहीं चलायी, तो भी और चलाते तो हमारे विरुद्ध ३०२ का मुकदमा दर्ज हो जाता। वैसे भी हमलावरों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। संख्या और हथियारों में भी वे हमसे ज्यादा थे। यदि हम गोली चलाते तो हम भी मारे जांते।" दूसरी ओर पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीराम अरुण तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ढिल्लों का दावा है, "पुलिस ने चार चक्र गोलियां चलायीं।"

यदि इस दावे को मान लिया जाये, तो पुलिस की तथाकथित चार चक्र गोलियां किसे लगीं? पुलिस उपमहानिरीक्षक श्रीराम अरुण बताते हैं, "घटनास्थल पर रजी हसन पुलिस की गोलियों का ही शिकार हुआ।" लेकिन बुलंदशहर में हुए रजीहसन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस कथन की पुष्टि नहीं होती। इस रिपोर्ट के अनुसार, रजी हसन के शरीर पर किसी धारदार हथियार के घाव थे। डाक्टरों की इस रिपोर्ट से पुलिस के उच्चाधिकारियों में हड़कम्प मच गया। आननफानन रजी हसन के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की योजना बन गयी। इस बार पुलिस कोई 'रिस्क' नहीं लेना चाहती थी। अतः पूरी तैयारी के बाद ४ फरवरी को मेरठ मेडिकल कालेज में दुबारा पोस्टमार्टम कराया गया। इस बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 'गनशॉट' होने की पुष्टि कर दी गयी। इस तरह पुलिस को अपनी मनचाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गयी। अब पुलिस इसी रिपोर्ट के आधार पर गोली चलाकर हस्तक्षेप करने का दावा कर रही है। लेकिन यह कार्य कैसे सम्पन्न हुआ, यह भी एक रहस्य है। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने में पुलिस ने मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिल्ली निवासी एक रिश्तेदार का सहारा लिया था।

सांखनी की राजनीतिक पहुंच: सांखनी गांव के सम्पन्न लोगों की राजनीतिक पहुंच भी कम नहीं है। मुहम्मद अली गुट के लोग जहां इसी जिले से चुने गये प्रदेश के श्रम मंत्री सईदुल हसन के खास लोग बताये जाते हैं, वहीं अभियुक्त शमशुल पर गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमा का वरदहस्त है। कहा जाता है कि मुहम्मद अली को फरमूदन के शव के साथ पुलिस सुरक्षा दिलाने के लिए श्रममंत्री सईदुल हसन ने जहांगीराबाद थाने को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन शमशुल चूंकि गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमा का खासमखास है, इसलिए जहांगीराबाद के थानाध्यक्ष ने मुहम्मद अली के साथ खानापूरी करने के लिए केवल एक उपनिरीक्षक और दो सिपाही भेजे। पुलिस की मौजूदगी में शमशुल ने ११ लोगों को मौत के घाट उतारा और पुलिस तमाशा देखती रही। इसका कारण भी शमशुल की राजनीतिक पहुंच ही थी।

५ फरवरी को सभी नामजद अयिभुक्तों के घर की कुर्की के दौरान जो समान मिला, उससे भी अभियुक्तों की ताकत और उनके अवैध कार्यकलापों का अंदाज लगाया जा सकता है। पुलिस को सभी अभियुक्तों के घर से अवैध असलहा, राजनेताओं के साथ अभियुक्तों के चित्र, शिकार के लिए निषिद्ध जानवरों की खालें आदि बरामद हुईं। मुख्य अभियुक्त शमशुल के घर से लगभग ४ ट्रक सामान की कुर्की हुई, जिसमें २ तमंचे, १४ कारतूस, १२ हथगोलों के साथ गाय की डेढ़ दर्जन से अधिक खालें भी शामिल थीं।

> शमशुल और उसके साथी हमारे खानदान के लोगों को मौत के घाट उतारते रहे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने हमलावरों पर एक गोली तक नहीं चलायी।

मोहम्मद हुसैन

अन्य घटनायें: वर्ष १९८९ की शुरुआत में ही मेरठ मण्डल में यह चौथा सामूहिक नरसंहार था। २६ जनवरी की सुबह मेरठ की सरधना तहसील के कपसाड़ गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गयी। उस सुबह सत्यपाल सिंह, हरि सिंह और बुद्धि सिंह अपने घर में टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे थे। अचानक हत्यारों ने घरों में घुस कर इन तीनों को गोलियों से भून डाला। हमलावर इतने दुस्साहसी थे कि वे इन तीनों के शव भी बैलगाड़ी में लादकर ले गये और उन्हें गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना के बाद की कार्रवाई के नाम पर गांव में पीएसी की गारद बिठा दी।

इस हत्याकांड के ठीक दो दिन बाद मेरठ में ही इंचौली थानाक्षेत्र के चिदौड़ी ग्राम में लगभग एक दर्जन सशस्त्र हमलावरों ने पांच व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आपसी रंजिश के कारण हुए इस हत्याकांड में तीन महिलायें भी मारी गयीं। यहां भी पुलिस के तम्बू गाड़ दिये गये। इन घटनाओं के पांचवे दिन परिक्षेत्र के बुलंदशहर जिले के साखनी गाव में पहली फरवरी को ११ लोग मार दिये गये। इन सामूहिक नरसंहारों की सनसनी अभी थमी भी न थी कि इसी ३ फरवरी को मेरठ में ही चांदी नगर थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में हमलावरों ने गांव के कंवल सिंह और भाईचंद की हत्या कर दी। बाद में पुलिस और ग्रामीणों ने हमलावरों की घेराबंदी करके उनमें से छह को मार गिराया।

कभी जब डाकू नरसंहार करते थे, हाहाकार मच जाता था। पुलिस के उच्चाधिकारियों को अपनी कुरसी खिसकती नजर आने लगती थी। पर आज मेरठ में नरसंहारों की श्रृंखला जारी है और पुलिस के आलाअफसरों के चेहरों पर शिकन तक नहीं है। मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक एसके मुखर्जी 'सांखनी कांड' को बात करने लायक घटना ही नहीं समझते। यही वजह थी कि जब उनसे फोन पर बातचीत के लिए वक्त मांगा गया, तो उनका कहना था, "यह तो एक सामान्य सी घटना है। ऐसी छोटी-मोटी घटनाओं के बारे में मुझसे क्या बात करेंगे? आप एसएसपी बुलंदशहर से बात कर लीजिए।"

ताजा स्थिति: घटना के एक सप्ताह बाद भी सांखनी में दहशत भरा सन्नाटा है। घरों से स्त्रियों के रोने की आवाजें आनी बंद हो गयी हैं। मारे गये व्यक्तियों के परिजनों के आंसू भी बहते-बहते थम चुके हैं। बचा है, तो बस दर्द जो आंखों से होते हुए दिल तक जा पहुंचा है और कभी-कभी सिसकियों के रूप में फूट पड़ता है। ३ फरवरी को गांव का दृश्य उस वक्त बड़ा दारुण था, जब सफेद चादरों से ढके नौ शव एक साथ कब्रिस्तान में दफनाये गये। गांव के अधिसंख्य व्यक्ति कुरेदने पर भी मुंह नहीं खोलते। गांव की हर गली में पुलिस के बूटों की आवाज गूंजती है। पूरा गांव पुलिस की छावनी बन गया है। इस समय गांव में ढाई प्लाटून पीएसी २० उपनिरीक्षक तथा ७५ सिपाही तैनात हैं। बुलंदशहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दयाशंकर सिंह तथा क्षेत्राधिकारी पुष्कर सिंह सांखनी गांव में ही कैम्प किये हुए हैं। ये अधिकारी भी मानते हैं, "जितनी फोर्स इस वक्त गांव में तैनात है, उसका दसवां भाग भी यदि पहली फरवरी को गांव में होता, तो यह नरसंहार नहीं होता।"

—बुलंदशहर से, राजीव सक्सेना

पंतनगर विश्वविद्यालय

जातीय झगड़ों का अखाड़ा

साठ के दशक में पंतनगर विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति लाने का अग्रदूत था, लेकिन आज वह गुटबंदी और मारपीट का मैदान-ए-जंग क्यों बन गया है?

बीजों की उन्नत किस्म विकसित करने के लिए विश्वविख्यात गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जातिवाद और क्षेत्रवाद के बीज भी अंकुरित हो गये हैं। पंतनगर स्थित एशिया के इस पहले कृषि विश्वविद्यालय में राजनेताओं और अध्यापकों ने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए छात्रों को पूरब-पश्चिम तथा जाट-ठाकुर के खेमों में बांटकर रख दिया है। क्षेत्रीयतावाद की यह लड़ाई खूनी जातीय संघर्ष में बदल गयी है, जिसकी परिणति है, खूनी झगड़े में ८ जनवरी, १९८९ को हुई एमएससी कृषि अर्थशास्त्र के २४ वर्षीय छात्र यदुवीर सिंह की हत्या। इस हत्या के बाद अनिश्चित काल के लिए बंद इस विश्वविद्यालय में दहशत के हालात पैदा हो चुके हैं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार ने इस झगड़े को बुनियादी तौर पर समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये, तो निश्चित तौर पर कई और प्रतिभाशाली छात्रों की इस झगड़े में जानें जा सकती हैं।

अतीत: पंतनगर विश्वविद्यालय की नींव १९६१ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी। अमरीका की भांति 'लैंड ग्रांट पैटर्न' पर आधारित यह एशिया का पहला विश्वविद्यालय था। १९६६ तक यह विश्वविद्यालय कोई विशेष प्रगति कृषि क्षेत्र में नहीं कर सका था। पर जब प्रशासक डा॰ ध्यानपाल सिंह कुलपति बने, तो वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने देश में हरित क्रांति लाने में पंतनगर विश्वविद्यालय को आधारभूत संस्था के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। डा॰ ध्यानपाल सिंह के कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही विश्वविद्यालय परिसर और प्रशासन में दलगत राजनीति ने पैर पसारने शुरू कर दिये थे। इसके बाद शिवप्रसाद पाण्डेय, धर्मपाल सिंह, एनएस माथुर, आनंद स्वरूप कुलपति बने। डा॰ धर्मपाल सिंह को छोड़ सभी आईएएस अधिकारी थे। इनमें कोई भी एक वर्ष से अधिक नहीं टिक सका। १९७८ में डा॰ धर्मपाल सिंह के समय में पंतनगर विश्वविद्यालय में भीषण गोलीकांड हुआ था। इस समय तक विश्वविद्यालय के अध्यापक, छात्र व कर्मचारी पूर्वी-पश्चिमी और पहाड़ी गुटों में बंट चुके थे। यहीं से वर्ग-संघर्ष के कीटाणु इस विश्वविद्यालय में पनपने लगे।

पंतनगर विश्वविद्यालय को उसकी गरिमा के अनुरूप ढालने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भारत के प्रथम बैच के आईएएस अधिकारी व स्वतंत्रता सेनानी कृपा नारायण को कुलपति बनाया। कृपा नारायण ने ६ वर्षों के कार्यकाल में पंतनगर विश्वविद्यालय को कृषि क्षेत्र की विश्व की अग्रणी संस्थाओं में लाकर खड़ा कर दिया। जब वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने यह जानते हुए भी कि कृपा नारायण से अच्छा प्रशासक पंतनगर विश्वविद्यालय को नहीं मिल पायेगा, उनका कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। चर्चा है कि जब वीर बहादुर सिंह सिंचाई मंत्री थे, तो प्रदेश के मुख्यसचिव की हैसियत से कृपा नारायण ने उनके भ्रष्टाचार की फाइल 'डील' की थी। संभवतः इसी कारण वीर बहादुर सिंह उनसे खफा थे। बताया जाता है कि इसी दौरान जोड़तोड़ कर तत्कालीन कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह ने अपने रिश्तेदार केएन कटियार को अस्थायी कुलपति बनवा दिया। ६ माह के कार्यकाल में कटियार ने प्रवेश परीक्षा में एसएससी के लिए निर्धारित ५० प्रतिशत अंक की मैरिट को अनदेखा कर गुपचुप ३३ प्रतिशत तक अंक पानेवालों को प्रवेश दे दिया। इनमें अधिसंख्य कुलपति कटियार के चहेते अध्यापकों के परिजन थे। उसी दौरान विश्वविद्यालय की आंतरिक परीक्षा प्रणाली का लाभ उठाकर प्रतिभाशाली छात्रों का मानसिक शोषण भी चालू हुआ। प्रतिभाशाली छात्रों के बजाय शोधकार्य अपने चहेते छात्रों और पुत्र-पुत्रियों को दिलाने की परम्परा भी कटियार के कार्यकाल में शुरू हुई, जिसकी परिणति में रश्मि अग्रवाल को आत्महत्या करनी पड़ी। कटियार ने विश्वविद्यालय के ट्रैक्टरों पर अपना नाम 'कनक' तक लिखवा दिया था। इन सबके बावजूद अध्यापकों का एक गुट चाहता था कि कटियार कुलपति बने रहें। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने किसी की नहीं चलने दी। उन्होंने अपने चहेते डा॰ महातम सिंह को पंतनगर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया।

महातम सिंह का आगमन: महातम सिंह जब काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि संस्थान के निदेशक थे, तो उन पर अपने पुत्र के नम्बर गलत ढंग से बढ़वाने का आरोप लगा था। पंचम सिंह नामक जो छात्र उनकी इस ज्यादती का शिकार हुआ था, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस कांड में महातम सिंह को विश्वविद्यालय से 'सस्पैंड' कर दिया गया

था। यह जानते हुए भी वीर बहादुर सिंह ने महातम सिंह को मात्र इसलिए कुलपति बनाया था, क्योंकि महातम सिंह पूरब (वाराणसी) के रहनेवाले थे और पूरब के लोगों के प्रति वह हमेशा मेहरबान रहते थे।

प्रोफेसर महातम सिंह के कुलपति बनने के बाद विश्वविद्यालय में गुटबाजी मुखर हो उठी। महातम सिंह ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर छांट-छांटकर पूरब के ठाकुरों को नियुक्त कर दिया। इससे पश्चिम के अध्यापकों में रोष बढ़ा। रही-सही कसर 'प्लांट ब्रीडिंग' विभाग में पीएचडी के लिए हुई परीक्षा के नतीजों में चुने हुए छात्रों की सूची ने पूरी कर दी। इस विभाग में मैरिट के अनुसार प्रथम पांच स्थान पानेवाले सभी छात्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (पूरब) के थे, जिनमें चार ठाकुर और एक ब्राह्मण था। पश्चिम के छात्रों और अध्यापकों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसी बीच महातम सिंह ने डा० पीएन सिंह को विश्वविद्यालय में नियुक्ति दे दी और उन्हें एसएमएस के पद पर बरेली परिसर में तैनात कर दिया। डा० पीएन सिंह पर १९७८ में विश्वविद्यालय में हुए नरसंहार में आचरणहीनता, गोली चलाने, चाकू चलाने और दगा कराने के संगीन आरोप लगे थे। डा० पीएन सिंह भी पूरब (देवरिया) निवासी है। उनकी इस नियुक्ति को लेकर बड़ा होहल्ला मचा और शिक्षक दो गुटों में बंट गये।

यह सब चल ही रहा था कि २३ जुलाई, १९८८ को 'फूड एवं न्यूट्रिशन विभाग' की एमएससी की छात्रा रश्मि अग्रवाल ने अपने शोध सहायक की प्रताडना के कारण आत्महत्या कर ली। विरोध में जो छात्र-आंदोलन भड़का उसमें पश्चिम के छात्रों की सक्रियता अधिक रही। कहा जाता है कि पंतनगर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष राजेश सिंह को कुलपति ने जातिवाद और क्षेत्रवाद का वास्ता देकर अपने साथ मिला लिया था। विरोध में छात्रों ने छात्रसंघ भंग कर दिया। पंतनगर विश्वविद्यालय अध्यापक संघ (पूटा) के विरोध के बावजूद कुलपति महातम सिंह ने छात्रों के दबाव में आकर गृहविज्ञान विभाग की डीन मिस एसएस ऊषा को निलम्बित कर दिया। बाद में विश्वविद्यालय बोर्ड ने इस निलम्बन को अवैध करार देकर मिस उषा को बहाल कर दिया!

प्रोफेसर महातम सिंह के कुलपति बनने के बाद विश्वविद्यालय में गुटबाजी मुखर हो उठी। महातम सिंह ने सभी महत्वपूर्ण पदों पर छांट-छांटकर पूरब के ठाकुरों को नियुक्त कर दिया। इससे पश्चिम के अध्यापकों में रोष बढ़ा।

रामऔतार प्रकरण: ६ सितम्बर, १९८८ को 'पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग' के छात्र रामऔतार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी। उसने जहर खा लिया था। रामऔतार को विश्वविद्यालय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इसी सिलसिले में क्रुद्ध छात्रों के ममक्ष आने पर कुलपति महातम सिंह ने वहीं डा० कक्कड़ की सेवायें समाप्त करने के आदेश जारी कर एक प्रति छात्रों को भी दे दी। बाद में विश्वविद्यालय बोर्ड के समक्ष महातम सिंह ने कहा कि उनसे छात्रों ने दबाव डालकर वह आदेश लिखाया था। यह मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि १६ सितम्बर को विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उसी दिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनिश्चित काल के लिए विश्वविद्यालय बंद करने की घोषणा कर दी। १२ घंटों के भीतर सभी छात्रावास खाली करा लिये गये। १७ अक्तूबर को कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद भी विश्वविद्यालय खोलने में एक माह का विलंब किया गया। बंदी के कारण कई छात्रों की डिग्री समय पर पूरी नहीं हो पायी। अधिसंख्य छात्रों ने प्रयोगात्मक फसलें उगा रखी थीं, वह उचित देखरेख के आभाव में नष्ट हो गयीं। शोध एवं प्रयोग के महत्वपूर्ण चरणों में पहुंच चुके शोध छात्रों को सिर्फ निष्कर्ष निकालकर शोधग्रंथ लिखना शेष था, वह भी अधूरा रह गया। बंदी के दौरान ५६ छात्र-छात्राओं को अनुशासन समिति के समक्ष पेश होना पड़ा। १८ छात्रों को ६ सितम्बर, १९८८ की रात रामऔतार की मौत के बाद चिकित्सालय में हुई मारपीट व तोड़फोड़ के आरोप में विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया और उनके परिसर में आने पर रोक लगा दी गयी। कई छात्रों पर अर्थदंड लगाया गया। इन सब से छात्र बौखला से उठे थे। जिन १८ छात्रों को विश्वविद्यालय से निकाला गया एक को छोड़ सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट थे। विश्वविद्यालय खुलते ही निकाले गये छात्रों ने परिसर के बाहर अनशन शुरू कर दिया।

२ दिसंबर, १९८८ को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी हल्द्वानी गये, तो खाद्यमंत्री हुकुम सिंह और सहकारिता राज्यमंत्री समरपाल सिंह उनके साथ थे। कुलपति महातम सिंह का आरोप है कि पश्चिम के छात्रों का निष्कासन रद्द कर उन्हें वापस लेने के लिए हुकुम सिंह ने उन पर दबाव डाला, क्योंकि छात्र उनके चुनाव क्षेत्र के थे। ऐसा ही आरोप वे समरपाल सिंह पर लगाते हैं। खाद्यमंत्री हुकुम सिंह ने 'माया' को बताया, "उस दिन कुछ छात्र मेरे पास आये और उन्होंने अपने निष्कासन की बात मुझसे कही। मैंने वहीं खड़े कुलपति महातम सिंह से पूछताछ की, तो उन्होंने छात्रों की अनुशासनहीनता की बात बतायी। मैंने छात्रों को डांटा। छात्रों ने एक पैर पर खड़े होकर वहीं कुलपति से क्षमायाचना की, तब स्वयं कुलपति ने खुद छात्रों से कहा कि वे विश्वविद्यालय में उनसे मिल लें। जहां तक छात्रों के मेरे चुनाव क्षेत्र के होने की बात है, यह निराधार है।"

इस घटना के बाद छात्र निरंकुश हो उठे कि वे कुलपति को दबाव में लेकर कुछ भी करा सकते हैं। साथ ही अनुशासन समिति के सभी सदस्यों ने विरोध में त्यागपत्र भी दे दिया कि कुलपति ने अनुशासन समिति का निर्णय बिना विचार-विमर्श के वापस लेकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक पर्वतीय छात्र द्वारा अपने सीनियर छात्रों के साथ बदसलूकी करने पर चितरंजन भवन छात्रावास के छात्रों में मारपीट हो गयी। मारपीट में पूरब का एक छात्र भी पिट गया था।

३० दिसंबर, १९८८ की रात विश्वविद्यालय में नवरंग समारोह था। समारोह के बाद पूरबी गुट के छात्रों ने चितरंजन छात्रावास के नीरज कुमार तोमर की पिटाई कर दी। नीरज पश्चिमी गुट का छात्र था। बदले में पश्चिम गुट के छात्रों ने पूरबी गुट के प्रभात कुमार सिंह की पिटाई की। उत्तेजित छात्रों ने पूरबी गुट के समर्थक पूर्व विधायक देव बहादुर सिंह के पुत्र समर सिंह की जीप भी क्षतिग्रस्त कर दी। इन सभी मामलों की रिपोर्ट लालकुआं थाने में दर्ज करायी गयी। ३१ दिसंबर को सभी विभागों के अध्यक्षों और अधिष्ठाताओं की बैठक तराई भवन (कुलपति निवास) में बुलायी गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा। कुलपति महातम सिंह 'एकेडेमिक कौंसिल' के निर्णय पर सहमत थे। पूरब के छात्रों ने पश्चिम के ४ छात्रों के निष्कासन की मांग की थी। ३१ दिसम्बर की रात जब बैठक चल रही थी, पूरबी गुट के लगभग पचास छात्र 'तराई भवन' गये। बताया जाता है कि उन्होंने कुलपति से कहा, "आप कार्यवाही क्या करेंगे, जो कुछ करना है, हम खुद कर लेंगे।" वहां से जाकर छात्रों ने पूरबी गुट के एक अध्यापक के यहां से कुलपति को फोन किया कि वे अपनी कार्यवाही करने जा रहे हैं। फिर छात्रों के उस गुट ने छात्रावास में जाकर पश्चिम गुट के यशपाल

सिंह और विनीत कुमार को बुरी तरह मारा-पीटा। यशपाल को अस्पताल पहुंचा कर देवेन्द्र सिंह नामक छात्र ने लालकुआं थाने में पूरब के १८ छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पूरब के छात्र रात एक बजकर पन्द्रह मिनट कर 'तराई भवन' से गये थे। कुलपति ने यह समय २ बजकर, तीस मिनट दर्शाया जबकि तीन बजे मारपीट की रिपोर्ट पंतनगर से आठ किलोमीटर दूर लालकुंआ थाने में लिखी जा चुकी थी। जब विभागाध्यक्षों और अधिष्ठाताओं की बैठक के निर्णय के अनुसार पश्चिम गुट के ४ और पूरब गुट के १८ छात्रों को परिसर से निकालने की बात आयी, तो कुलपति ने अपना निर्णय बदल दिया। पश्चिम के जाट छात्रों के समर्थक अध्यापकों तथा 'पूटा' का आरोप है कि कुलपति ने क्षेत्रवाद तथा जातिवाद के चलते यह सब किया, क्योंकि सभी पूरब के छात्र ठाकुर थे। यहीं से छात्रों के बीच चल रहे जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष में अध्यापक भी शामिल हो गये।

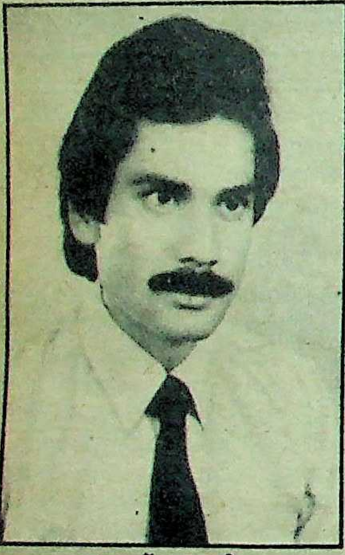

भूपाल सिंह माकुनी

पंतनगर विश्वविद्यालय में कुलपति ऐसा आईएएस अधिकारी होना चाहिए जो कुशल प्रशासक भी हो। साथ ही वह दक्षिण भारत का हो, ताकि जाति व क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय ले सके।

शांति समिति की भूमिका: २ जनवरी, १९८९ को गठित शांति समिति के जरिये चार जनवरी को छात्रों के दोनों गुटों में समझौता हो गया कि अब वे एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। लेकिन ६ जनवरी की सुबह लगभग चार बजे पश्चिम गुट के छात्र भुवनेश कुमार पर छात्रावास में कमरे का दरवाजा तोड़कर लाठी, डंडों और चाकू से हमला किया गया। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों में डा० पीएन सिंह (एसएमएस) उदयवीर सिंह, राजेश सिंह तथा कुछ अन्य लोग शामिल थे। इससे तनाव एक बार फिर बढ़ा।

६ जनवरी की शाम पंतनगर विश्वविद्यालय अध्यापक संघ (पूटा) ने एक प्रस्ताव पारित किया कि ऐसे हालात पैदा हो गये हैं, जिसमें किसी की हत्या भी हो सकती है। यदि कुलपति इन हालात पर काबू पाने में अक्षम हैं, तो इस्तीफा दे दें। जिस समय पूटा के सदस्य कुलपति को ज्ञापन दे रहे थे, प्रशासनिक खण्ड कमेटी रूम की खिडकियों से पूरबी गुट के छात्र हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पश्चिमी गुट के छात्र भी वहां पहुंचे। उन्होंने रजिस्ट्रार से ७ दिनों तक परीक्षाएं टालने के लिए अनुरोध किया। बाहर तैनात पीएसी के कारण दोनों गुट आपस मे नहीं भिड़ पाये। इसी खण्ड में कुलपति कार्यालय भी है। कुलपति ने अध्यापकों को ऊपर आने की अनुमति नहीं दी और स्वयं नीचे आकर ज्ञापन लिया, फिर वापस अपने कार्यालय में चले गये। ७ जनवरी शांति से गुजरी। यह तय हो गया कि कुलपति दो दिनों बाद दोनों गुटों के छात्रों को सम्बोधित करेंगे।

लेकिन ८ जनवरी की शाम परिसर में गांधीभवन तिराहे पर पश्चिम के छात्र प्रमोद कुमार कुंडू पर हमला हुआ। हमलावरों में डा० पीएन सिंह, उदयवीर सिंह सहित पूरबी गुट के लोगों के नाम आये। छात्र कुलपति के पास गये। कुलपति मौन रहे। पंतनगर पुलिस चौकी-इंचार्ज कृष्णा थापा ने मौके की नाजुकता देख डा० पीएन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस, छात्रावासों की तलाशी लेने की अनुमति मांगती रही। चितरंजन भवन के वार्डन डा० हरिहर राम कुलपति तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के यहां छात्रावासों की तलाशी दिलाने के लिए अनुमति लेने के लिए भागते रहे, पर अनुमति नहीं मिली। इसी दौरान विद्युत सप्लाई में खराबी आ जाने की वजह से दिल्ली सहित पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूब गया। पूरबी गुट का उदयवीर सिंह भयवश चितरंजन भवन में अपने मित्र के कमरे में आ छिपा। पश्चिम गुट के छात्रों ने उसे खोज निकाला और राड, लाठी, डंडों से बुरी तरह मारा। उदयवीर सिंह के सिर में चोट आयी और वह मर गया। इस के काफी देर बाद नैनीताल के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एनआर श्रीवास्तव, उपाधीक्षक प्रभात कुमार पंतनगर पहुंचे। कुलपति ने तलाशी का मौखिक आदेश दिया। पुलिस ने परिसर में कर्फ्यू लगा दिया। उदयवीर सिंह की मौत की खबर गुप्त रखकर सुबह पांच बजे तक सभी छात्रावास खाली करा लिये गये। रातभर चली मारपीट में लगभग ५० छात्र घायल हुए। जिनमें अधिकांश पूरब के थे। पूरब के एक छात्र को सुबह होते ही छूरा भोंक दिया गया।

उदयवीर सिंह की मृत्यु की पहली रपट सुरक्षा अधिकारी रबैल सिंह ने लिखायी थी। फिर पूरबी छात्रों को तराई भवन में बैठा कर कुलपति ने अपने सामने पश्चिम गुट के छात्रों के खिलाफ उदयवीर सिंह की हत्या की रिपोर्ट लिखवायी और खुद एक पत्र लिखकर उसे लालकुआं थाने में दर्ज करने की सिफारिश की। पूरे प्रकरण का महत्वपूर्ण पहलू तो यह था कि जब भी पश्चिम के छात्रों पर हमले हुए, मत्स्यपालन विभाग का नवनिर्मित विश्राम गृह "मीनाक्षी भवन' ही पूरबी गुट का अड्डा रहा। इस विभाग के प्रमुख कुलपति के खास माने जाते हैं। वहीं पश्चिम गुट के छात्रों को प्रोफेसर हरपाल सिंह का संरक्षण मिलता रहा।

डा० यशपाल सिंह राठी

फिर छात्रों के उस गुट ने छात्रावास में जाकर पश्चिम गुट के यशपाल सिंह राठी और विनीत कुमार को बुरी तरह मारा-पीटा। यशपाल को अस्पताल पहुंचाकर देवेंद्र सिंह नामक छात्र ने लाल कुआं थाने में पूरब के १८ छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी।

कुलपति महातम सिंह ने इस संबंध में 'माया' को बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हमलावर गुट की मदद की, इसी कारण उदयवीर सिंह मारा गया। जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस आरोप को पूर्णतः असत्य बताते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि यदि पुलिस इतनी तत्परता न दिखाती, तो पचासों छात्र मारे जाते। कुलपति महातम सिंह का आरोप है कि पश्चिम गुट के कुछ अध्यापकों ने अपने स्वार्थों के लिए यह झगड़ा कराया। कुलपति के अनुसार, "इसमें, एनएस वर्मा, डा० यशपाल सिंह राठी, डा० विक्रम सिंह, डा० हरपाल सिंह आदि लोग हैं। ये लोग पश्चिम गुट के छात्रों को शह देते हैं। जब डा० महाराज सिंह निदेशक (शोध) थे, तो उन्होंने सौ प्रतिशत भरती पश्चिम के लोगों की थी। यहां तक कि मुझे किसान यूनियन के नेता महेन्द्र सिंह टिकैत ने पत्र द्वारा धमकी दी है कि १७ जनवरी को सिसौली में हुई मासिक पंचायत में यह निर्णय लिया गया है कि यदि पश्चिम के छात्रों पर लगा हत्या का अभियोग नहीं हटाया गया, तो वे आन्दोलन करेंगे।"

पश्चिम-पूरब का यह जहर पंतनगर के समीपवर्ती किच्छा, रुद्रपुर, हल्द्वानी तथा तराई में तेजी से फैल रहा है। किच्छा में तो ३१ दिसंबर, १९८८ को पूरब के एक छात्र नवीन सिंह ने पश्चिम के एक छात्र पर चाकू से हमला भी किया था। फिर किच्छा के फार्महाउस के दो प्रभावशाली मालिक पूरब तथा पश्चिम के छात्र के पक्ष-विपक्ष में थाने भी पहुंचे थे। रुद्रपुर में पूरब व पश्चिम के गुट ने खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ सभायें कीं। इतना ही नहीं मेरठ तथा वाराणसी में तो प्रतिक्रिया स्वरूप तोड़फोड़ तथा पोस्टर बाजी तक हुई।

डा० पीएन सिंह, जिन्हें तीन मामलों में मारपीट का अभियुक्त बनाया गया है, ने 'माया' को बताया, "मुझे रंजिशवश पश्चिम के लोगों ने फंसाया है। पुलिस ने मेरा पैर तोड़ डाला। रही 'कन्डक्ट प्रोबेशन' के बाद विश्वविद्यालय में नियुक्ति पाने की बात तो ३३ ऐसे अध्यापक परिसर में नौकरी कर रहे हैं, जिन्हें 'कन्डक्ट प्रोबेशन' मिला हुआ है।" पीएन सिंह कुलपति को अवसरवादी तथा कुरसी बचाने के लिए कुछ भी करनेवाला करार देते हैं।

पश्चिम गुट के अध्यापकों का आरोप है कि महातम सिंह ने कृषि विभाग में ही चार ठाकुरों सहित अन्य वर्गों के एक-एक व्यक्ति को विभागाध्यक्ष या अधिष्ठाता बना रखा है। पर एक भी जाट या पश्चिम के किसी व्यक्ति को ऐसा कोई पद नहीं दिया। महातम सिंह पर ठाकुरों का पक्ष लेने का आरोप है। 'पूटा' के सदस्यों के अनुसार, सितारगंज फार्म से कृपा नारायण ने एमपी सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला था, उन्हें वापस लिया गया। मत्स्य पालन विभाग के प्रोफेसर सीएस सिंह ने पुत्री की शादी के बहाने आठ शोध सहायकों से कमरे खाली कराये और फिर वहीं जम गये। इसी प्रकार एपी सिंह, जिनका चयन शोध सहायक के लिए नहीं हो सका था, को बरेली में एसएमएस नियुक्त कर दिया गया। इतना ही नहीं कृषि अर्थशास्त्र विभाग के एसए अली जिनके पास १२ वर्ष का अनुभव भी है, को प्रोन्नति देने के स्थान पर उनके छात्र रहे एसपी सिंह को उनके ऊपर बैठा दिया गया। इन सब आरोपों का उत्तर कुलपति नहीं देते हैं।

घोटालों का मुख्य केन्द्र: पंतनगर विश्वविद्यालय में अध्यापकों व अधिकारियों के बीच गुटबंदी का एक बहुत बड़ा कारण वहां का फार्म भी है। लगभग ११,७०० एकड़ का यह फार्म घोटालों का मुख्य-केंद्र और आय का मुख्य स्रोत हैं। कुलपति ध्यानपाल सिंह के कार्यकाल में यह फार्म एक करोड़, ६० लाख रुपए के लाभ में था, लेकिन अब ६० लाख के घाटे में है। फार्म के मैनेजर को कृषि का विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन महातम सिंह ने कृषि अभियंता को मैनेजर बना रखा है। फार्म हाउस में औसतन प्रति सप्ताह एक चोरी होती है।

मोहन गिरी

कुलपति महातम सिंह को हटाये बिना विश्वविद्यालय खोलना मूर्खता होगी। कुलपति ने छात्रों में जातिवाद के बीज तो बोये ही हैं, साथ ही वे अपनी खाल बचाने और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को बदनाम करने के लिए भ्रामक प्रचार भी करवा रहे हैं।

कुलपति ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन कर यह बयान दिया कि पंतनगर विश्वविद्यालय के अध्यापक परिसर में गुण्डागर्दी कराते हैं। उनके इस बयान के बाद अध्यापक पूर्णतः कुलपति के खिलाफ हो गये हैं। परिसर में पूरबी गुट ने यह भी प्रचारित किया कि वीर बहादुर सिंह के खास होने के कारण मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी कुलपति महातम सिंह का विरोध करते हैं। स्वयं महातम सिंह ने भी इस प्रकार के बयान दिये हैं।

पंतनगर विश्वविद्यालय की इन घटनाओं की पर्वतीय क्षेत्र के सभी विद्यालयों में प्रतिक्रिया हो रही है। पंतनगर विश्वविद्यालय में छात्रसंघ न होने के कारण छात्रों ने कुमायूं विश्वविद्यालय से सहयोग मांगा था। कुमायूं विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष मोहन गिरी गोस्वामी का कहना है, "कुलपति महातम सिंह को हटाये बिना विश्वविद्यालय खोलना मूर्खता होगी। कुलपति ने छात्रों में जातिवाद के बीज तो बोये ही हैं, साथ ही वे अपनी खाल बचाने और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को बदनाम करने के लिए भ्रामक प्रचार भी करवा रहे हैं।"

कुमायूं के लोकप्रिय छात्रनेता भूपाल सिंह भाकुनी, जिन्होंने पूरबी और पश्चिमी छात्रों में सुलह कराने का काफी प्रयास भी किया के विचार में, "पंतनगर विश्वविद्यालय में कुलपति ऐसा आईएएस अधिकारी होना चाहिए जो कुशल प्रशासक भी हो। साथ ही वह दक्षिण भारत का हो ताकि जाति व क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय ले सके।"

पंतनगर कर्मचारी संगठन 'पूटा' तथा नैनीताल के अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय में शांति स्थापित करने के लिए कुलपति महातम सिंह को हटाना जरूरी मानते हैं। महातम सिंह ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का आग्रह प्रदेश सरकार से किया है। प्रदेश सरकार की ओर से गृहमंत्रालय ने केन्द्र से सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है।

पंतनगर विश्वविद्यालय में फैले जातिवाद व क्षेत्रवाद के झगड़े को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। मुख्यमंत्री ने 'माया' को बताया, "पंतनगर विश्वविद्यालय की घटनाओं से मैं बहुत आहत हुआ हूं। वहां के अध्यापकों और बुद्धिजीवियों को छात्रों को समझाबुझाकर क्षेत्रवाद और जातिवाद के झगड़ों से अलग रखना चाहिए। मेरी राय में तो जातीयता व क्षेत्रीयता के नाम पर हुए झगड़ों को वहीं दबा देना चाहिए। सरकार की ओर से विश्वविद्यालय में शांति स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। मेरे खिलाफ वहां क्या प्रचार हुआ है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।" बहरहाल, इतना तय है कि यदि पंतनगर विश्वविद्यालय में चल रहे इस संघर्ष को समाप्त कराये बिना ही विश्वविद्यालय खोला गया, तो परिसर खूनी झगड़ों का खुला अखाड़ा बन जायेगा।

—पंतनगर से, निशीथ जोशी

इंदिरा गांधी स्वर्ण कप हाकी

स्टिक किसी के पास, गेंद किसी के पास

यह तो सच ही है कि लखनऊ में ध्यानचंद हाकी स्टेडियम बन जाने से हाकी की गतिविधियों को एक नया जीवन मिल गया है। स्पोर्ट्स कालेज परिसर में पिछले वर्ष एस्ट्रो टर्फ बिछ जाने के बाद से ही ढेर सारी प्रतियोगिताओं के आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि यहां अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन पहले महज एक सपना था।

वैसे तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी प्रतियोगिता अपने उद्घाटन वर्ष से ही बाराणसी में होनी थी, पर भला हो अंतरराष्ट्रीय हाकी संघ का जिसने यह फरमान जारी कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा की मान्यता की पहली शर्त टर्फ ग्राउंड होगा। जब यह घोषणा हुई थी, तब समय बहुत कम था और प्रदेश में टर्फ बिछ नहीं सकता था, लिहाजा दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में तीन साल पहले देश की पहली और अकेली अंतरराष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का मेला लगा। इस प्रतियोगिता को कराने की जिम्मेदारी ली 'प्ले मेकर्स' नाम की संस्था ने जो आज भी इंदिरा गांधी स्वर्ण कप हाकी के आयोजन से जुड़ी हुई है। बावजूद इसके 'प्ले मेकर्स' की स्थिति भंगियों जैसी है, क्योंकि उसकी इस प्रतियोगिता में कोई पूछ नहीं है। यह बात इसी से समझी जा सकती है कि पचीसों लाख रुपए देने के बाद भी स्टेडियम की विशिष्ट दीर्घा में बैठने तक का भी उसे अधिकार नहीं प्राप्त है। पर व्यावसायिक घराने से सम्बद्ध इस संस्था को मान-सम्मान से क्या लेना-देना? उसे तो बस 'अर्थ' से मतलब है।

खेल में खेल : 'प्ले मेकर्स' की हैसियत तो इस बार तीसरे इंदिरा गांधी स्वर्ण कप में और भी हास्यास्पद हो गयी, क्योंकि पहले झूठ बयानी के कारण संयोजन समिति की जो किरकिरी हुई, उससे चिढ़कर संयोजन समिति के सेक्रेटरी राज भार्गव ने पूरा दोष प्रायोजकों पर मढ़ डाला।

जीत-दर-जीत की खुशी : पाकिस्तानी टीम

हुआ यह कि राज भार्गव १४ जनवरी से शुरू इस स्पर्धा की पूर्व संध्या को सभी से यही कहते रहे कि उद्घाटन मैच मेजबान भारत बनाम केन्या के बीच ही होगा। समाचार एजेंसियों और लगभग सभी पत्रों ने यही लिखा भी, पर संयोजन समिति के अध्यक्ष लोकपति त्रिपाठी व तकनीकी सचिव जमन लाल शर्मा ने शाम को ही कह दिया था कि केन्या के न आने से कार्यक्रम में फेरबदल होगा। पर राज भार्गव देर रात तक प्रेस से 'गेट टुगेदर' में कार्यक्रम के न बदले जाने की बात दोहराते रहे। यहां तक कि एजेंसियां खबरों का खंडन करने को दौड़ पड़ीं।

भार्गव साहब की बात में आकर आकाशवाणी सुबह तक यही चिल्लाता रहा कि उद्घाटन मैच भारत बनाम केन्या के बीच होगा, लेकिन यह सफेद झूठ बोला गया था। जब राज भार्गव का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि लोकपति त्रिपाठी एवं जमन लाल शर्मा ने तो कार्यक्रम के बदल जाने की सूचना दी है, तो भार्गव का जवाब था, "प्रतियोगिता का आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी मैं हूं, मेरी ही बात सही है। आप गलत लोगों से मिलेंगे, तो आपको गलत सूचना मिलेगी ही।" हालांकि बाद में उन्होंने लिखित रूप से इसके लिए सफाई दी कि प्रायोजक की ओर से गलत सूचना पाकर उन्होंने यह घोषणा की थी। 'प्ले मेकर्स' भी अपने ऊपर लगे झूठे आरोप से तिलमिला गया था। उसके प्रवक्ता ने कहा, "हम प्रतियोगिता के प्रायोजक जरूर हैं, पर आयोजन से हमारा कोई मतलब नहीं है। किसका मैच किससे होगा, इसकी जिम्मेदारी आर्गनाइजेशन कमेटी व भारतीय हाकी संघ की है, हमारी नहीं।"

जाननेवाले जानते हैं कि राज भार्गव का पहले संबंध क्रिकेट से था। वे इसके खिलाड़ी भी रहे, पर एक कमेंटेटर के रूप में वे एक बार इतना गलत बोल गये कि फिर वे छोटे परदे पर अपना क्रिकेट ज्ञान जताते नजर नहीं आये। चूंकि वे प्रदेश के खेल सचिव भी रह चुके हैं, लिहाजा टेबल टेनिस में उनकी घुसपैठ हुई और वे उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बन बैठे। इसी के माध्यम से वे भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की सर्वोच्च कुरसी (अध्यक्ष पद) पर विराजमान होना चाहते थे। साल के शुरू में भारतीय टेबल टेनिस

एसोसिएशन के चुनाव भी हुए, पर अध्यक्ष पद के इस बहुचर्चित दावेदार ने अंत में न लड़ना ही उचित समझा, क्योंकि उन्हें कहीं से भी समर्थन की उम्मीद नहीं थी। महत्वाकांक्षा ने जोर मारा, तो वे हाकी से भी जुड़ गये। सत्ता के गलियारे में अपनी अच्छी पहुंच रखनेवाले इस आईएएस को इंदिरा गांधी स्वर्ण कप की संयोजन समिति का सचिव बनने में कोई समय नहीं लगा।

और इस समय इस कुरसी पर बैठकर वे सभी को नीचा दिखाने में लीन हैं। दूर की बात तो छोड़ दीजिए, इस व्यक्ति ने तो उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को पूरी तरह ठेंगा दिखा रखा है। इतना बड़ा हाकी का अंतरराष्ट्रीय मेला लगा, पर उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कंट्रोल की एक प्रतिशत भी भागीदारी नहीं रही, बल्कि आयोजन के नाम पर जो फीस प्रदेश में हाकी की गतिविधियों की जिम्मेदार बोर्ड को मिलनी चाहिए थी, वह भी नहीं मिली। दरअसल, जो कमजोर होते हैं, वही सहारा ढूंढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो हाकी व फुटबाल की मान्य इकाई है वह केवल कागजी प्रतीत होती है। कोई ठोस गतिविधि नहीं, लिहाजा बड़े टूर्नामेंट का बड़ा अधिकारी उन्हें क्यों घास डाले? कायदे से पिछले वर्ष के बोर्ड को इस आयोजन के फलस्वरूप १८ हजार रुपए पाने का अधिकार था और इस बार बोर्ड को २५ हजार रुपए फीस के रूप में मिलने थे।

उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड वैसे भी निष्क्रिय रहता है, पर इस तमाशे ने तो उन्हें और भी नंगा कर दिया। सबसे शर्मनाक स्थिति यह रही कि भारतीय हाकी संघ ने अपनी फीस बढ़ा ली, पर वह अपनी इकाई को न्याय नहीं दिला पाये। भारतीय हाकी संघ की फीस जहां पिछली बार ७५ हजार रुपए थी, वहीं वह इस बार एक लाख रुपए ले बैठा।

हाकी संघ का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहां क्यों नहीं आया, इसके पीछे भी एक कहानी है। हाकी संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, संपत्नीक यहां पिछली बार आये थे। उनकी पत्नी के पेमेंट को लेकर चिकचिक हुई थी। बम्बई से सम्बद्ध इस पदाधिकारी को इस बार बुलाने की हर स्तर पर कोशिश हुई, पर वे नहीं आये, न ही उनकी टीम। माना कि संयोजन समिति ने उन्हें नजरअंदाज किया, पर हाकी के हित में उन्हें यहां होना चाहिए था, क्योंकि इस समय भारतीय हाकी टीम नवनिर्माण के दौर में है। आधे से अधिक नये व युवा चेहरों वाली भारतीय टीम को भविष्य में संवरना है। पर अपना हित पहले है, हाकी तो बाद की चीज है, इनके लिए।

प्रतियोगिता का सरकारीकरण तो पहले ही हो चुका था, इस बार इन अजूबों के बाद प्रतियोगिता का राजनीतीकरण भी हुआ। आश्चर्य की बात है कि खेलमंत्री को प्रारम्भ में तो भुला दिया गया था। यही नहीं 'दीदी' के नाम से चर्चित श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी इस अंतरराष्ट्रीय हाकी में शुरू में कहीं नहीं थीं। यहां तक कि कई मैचों में उप मंत्रियों तक को मुख्य अतिथि के पद से सुशोभित किया गया, जब सुगबुगाहट बढ़ी, तो एक दिन वे काफी बाद में आयीं, फिर पूरी प्रतियोगिता में उनके दर्शन नहीं हुए। न ही वे उद्घाटन में थीं, न समापन समारोह में ही उनकी झलक दिखी। प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन और उसमें खेलमंत्री की किसी भी स्तर पर भागीदारी न रहे, तो इसे क्या कहा जाये?

उपविजेता होने का सम्मान: हालैंड की टीम

छाया: राजेंद्र कुमार

—लखनऊ ब्यूरो

पाक की बादशाहत बरकरार

लगता है कि पाकिस्तान की हाकी टीम को लखनऊ और इंदिरा गांधी स्वर्ण कप दोनों ही रास आ गया है। पिछले वर्ष भी पाकिस्तान ने यहां जीत दर्ज की थी और इस बार भी पाकिस्तानी टीम ने अपनी श्रेष्ठता बरकरार रखी। इस तरह तीन वर्षों की इंदिरा गांधी स्वर्ण कप हाकी में पाकिस्तान की यह लगातार दूसरी विजय रही। जबकि हालैंड ने एक बार स्वर्ण कप ट्राफी पर कब्जा जमाया था और इस बार उसे उपविजेता की ट्राफी से ही संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम इस बार न केवल जीती ही, बल्कि उसने फाइनल में हालैंड को पराजित कर अपने कई हिसाब-किताब पूरे भी कर लिये। एक तो उसने ग्रुप मैच में हुई हार का बदला शानदार ढंग से फाइनल में लिया, दूसरे सोल ओलम्पिक में हुई पुरानी हार का भी बदला ले लिया।

९ दिन की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली ८ टीमों को २ ग्रुपों में बांटा गया था। 'ए' ग्रुप में गत विजेता पाकिस्तान के अलावा हालैंड, स्पेन और मलेशिया की टीमें थीं, जबकि 'बी' ग्रुप में मेजबान भारत, गत उपविजेता सोवियत संघ, केन्या और पोलैंड की टीमें थीं।

सोल ओलम्पिक में छठा स्थान पाने वाली भारतीय टीम भी इस बार सेमीफाइनल में पहुंच गयी, पर सबसे बड़ा उलट फेर यह हुआ कि गत उपविजेता सोवियत संघ अंतिम चार में पहुंचने से वंचित रह गया। पर इससे भी बड़ा अचरज केन्या की टीम ने प्रस्तुत किया। बगैर एक भी मैच जीते वह सेमीफाइनल में जा पहुंची जबकि ग्रुप 'ए' से हालैंड और पाकिस्तान की चुनौती सेमी-फाइनल में पहुंची।

भारत और पाकिस्तान की टक्कर सेमी-फाइनल में हुई और बेहतर खेलकर भी भारतीय टीम ३-० से हार गयी, क्योंकि उसने मैदानी गोल करने के ढेर सारे अवसर गंवाने के साथ ही पेनाल्टी भी बेकार किया।

पाकिस्तान टीम फाइनल में जीत के प्रति आश्वस्त थी और वह इसी संकल्प को लेकर खेली। उसकी रक्षण पंक्ति तो सुदृढ़ थी ही, साथ ही आक्रमण पंक्ति ने पैनेपन की और भी ऊंचाई नापी। शाहबाज के नेतृत्व में पाक का आक्रमण देखने लायक था। पाकिस्तान के लिए गोल पेनाल्टी कार्नर पर कप्तान काजी मोहिब और ताहिरजमा ने किये जबकि हालैंड की ओर से एक गोल उतारने का श्रेय कोटो परलेक्टि ने किया।

भारत पिछली बार जहां पांचवें स्थान पर पिछड़ गया था, वहीं इस बार तीसरे स्थान पर आने में सफल रहा।

◆

रोबोट द्वारा तैयार टेलीफोन

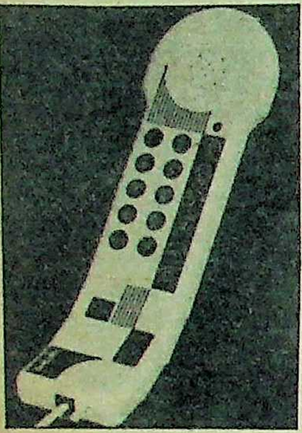

इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। छोटी से छोटी चीजों से लेकर आदमकद मशीनों में भी इलेक्ट्रोनिक्स ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। फिलहाल कोई ऐसा टेलीफोन नहीं बना था, जो शुद्ध रूप से इलेक्ट्रोनिक्स तकनीक पर आधारित होता। किंतु हाल में अमरीकी स्विसेल इनकारपोरेशन की स्विट्जरलैंड स्थित इकाई ने ऐसा टेलीफोन बना दिया है जो आकार-प्रकार में अकेला है। साथ ही इस टेलीफोन का वजन इतना कम है कि छोटा बच्चा भी इसे बड़ी आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकता है। स्विसेल कंपनी द्वारा बनाये गये इस टेलीफोन का ब्रांड नाम स्विसेल ही है।

इस टेलीफोन की विशेषता यह है कि इसको यांत्रिक मानव (रोबोट) तैयार करते हैं। उल्लेखनीय है कि यह विश्व का पहला, रोबोट द्वारा बनाया गया टेलीफोन है। टेलीफोन के किसी भी हिस्से को खोलने पर कहीं तार का नामोनिशान नहीं मिलता, क्योंकि इस टेलीफोन को पूरी तरह तारविहीन बनाया गया है। कंपनी के अध्यक्ष पीटी बकल्स के अनुसार टेलीफोन का वजन तार का इस्तेमाल न किये जाने से ही बहुत कम हो गया है। स्विसेल टेलीफोन में मशीन या तार की जगह क्रेडिट कार्ड के आकार का एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिस पर सरकिट बना होता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि टेलीफोन की कंपनी पांच साल की गारंटी भी देती है। फिलहाल स्विसेल टेलीफोन यूरोप के बाजारों में बिक रहा है, किंतु कंपनी शीघ्र ही इनका एशियाई देशों में निर्यात भी शुरू करने जा रही है।

गोल्फ स्कोर कार्ड

गोल्फ खिलाड़ियों के स्कोर की चिंता को मद्देनजर रखते हुए कैलीफोर्निया (अमरीका) स्थित सीको इलेक्ट्रोनिक कंपनी ने 'इलेक्ट्रोनिक गोल्फ कार्ड' बना दिया है, जो खिलाडियों को उनके स्कोर का लेखा-जोखा पलक झपकते सामने लाने में सहायक है। उक्त गोल्फ स्कोर कार्ड में एक समय में चार खिलाड़ियों के स्कोर सुरक्षित रखे जा सकते हैं। बैटरी से चलने वाले, क्रेडिट कार्ड के आकार के इस उपकरण में गोल्फ के १८ चरण तक के स्कोर का लेखा-जोखा एकत्र किया जा सकता है।

GOLF SCORECARD
A B C D

चूंकि इलेक्ट्रोनिक स्कोर कार्ड का इस्तेमाल मुश्किल नहीं है, इसलिए कागज-कलम के झंझट से छुटकारा चाहनेवाले गोल्फ के शौकीनों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शुरू में इलेक्ट्रोनिक स्कोर कार्ड का परीक्षण करने के लिए कई बड़ी प्रतियोगिताओं में इसके साथ कागज-कलम का भी प्रयोग किया गया किंतु नतीजे सही पाये गये।

गोल्फ खिलाड़ी इस उपकरण का इस्तेमाल अपने खेल की कमियों को जानने के लिए भी करते हैं। इस कार्ड पर एक हिस्से में लिक्विड क्रिस्टल लगा होता है जिस पर चारों में से किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गये खेल का विश्लेषण बटन दबाते ही आ जाता है। साथ ही, इसमें ऐसे बटन भी लगे होते हैं जिनको दबाने पर यह भी पता चल सकता है कि किसी विशिष्ट 'होल' पर खिलाड़ी का स्कोर क्या था और 'ग्रीन' तक पहुंचने में उसे कितने स्ट्रोक मारने पड़े थे। स्कोर कार्ड में महीना, दिन और समय सुरक्षित रखने का भी बटन लगा है। फिलहाल यह उपकरण अमरीका में उपलब्ध है। शीघ्र ही इसका अन्य यूरोपीय तथा एशियाई देशों में निर्यात होगा।

चित्र युक्त घड़ियां

उत्पादनों की बिक्री बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न कंपनियां नयी से नयी नीति अपनाती हैं। जहां कुछ कंपनियां विज्ञापनों में सेक्सी मॉडलों का इस्तेमाल करती हैं, वहीं बहुतेरी ऐसी हैं जो अपने उत्पादन की खपत बढ़ाने के लिए विज्ञापनों में 'दादी अम्मा' और 'मास्टरजी' जैसे प्लाट का इस्तेमाल करती हैं। किंतु अमरीका की घड़ी बनानेंवाली टाइमेक्स एवं कोडेक कंपनियां इस क्रम में काफी आगे निकल गयी हैं। इन कंपनियों ने ऐसी घड़ियां बनायी हैं जिनके डायलों में मनमाफिक तस्वीरें लगवायी जा सकती हैं। जाहिर है, इतने आधुनिक युग में भी लोगों की 'अपनों' के प्रति जो भावनाएं हैं, उनको भुनाने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। अभी तक तो स्वर्गीय पिता, पत्नी या प्रेयसी की तस्वीर कमरों के फ्रेम या जेब में रखे पर्सों तक ही मौजूद रहती थी, अब तो कलाई पर बंधी घड़ी को ही देखकर उनकी याद ताजा की जा सकती है।

तकनीकी दृष्टि से तो इन घड़ियों में कोई विशेष बात नहीं है, सिवाय इसके कि इन घड़ियों के डायल कुछ इस तरह तैयार किये जाते हैं, ताकि उनमें तस्वीर आसानी से चस्पां की जा सके। बस ग्राहक को करना इतना होता है कि वह काउंटर पर जाकर घड़ी पसंद कर ले और अपना पसंदीदा चित्र दे दे। छह दिन के अंदर ही उसके दिये हुए चित्र की तरह दूसरा चित्र तैयार करके डायल पर लगा दिया जाता है जिसका अतिरिक्त पैसा देना होता है। जरूरत पड़ने पर चित्र बदलवाये जा सकते हैं। फिलहाल ये चित्र-युक्त घड़ियां यूरोप में खूब बिक रही हैं। शीघ्र ही टाइमेक्स तथा कोडेक के कुछ काउंटर एशियाई देशों में भी खुलनेवाले हैं।

—संयोजन : तारिक खान

ल० रा० पेंढारकर

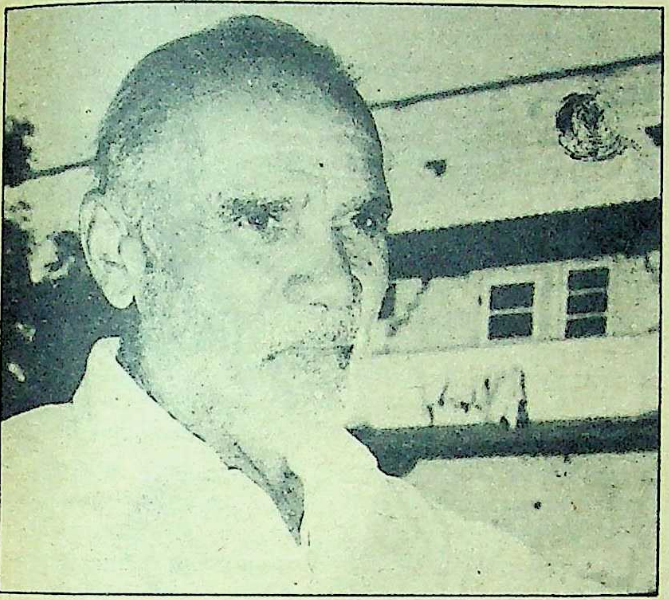

लक्ष्मण राव पेंढारकर का नाम कलाकारों के बीच अपरिचित नहीं है। उन्नासी साल की उम्र में भी उनकी सक्रियता, उत्साह व रचनात्मकता नौजवान कलाकारों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इंदौर में जन्मे पेंढारकर का अधिकतर जीवन राजस्थान के गांवों, लोकजीवन और शिल्प को कैनवास पर उतारते बीता है। उनके स्कैच व चित्रों की पुस्तक 'ग्लिम्प्सेस आफ रूरल राजस्थान' तो अमरीकी आर्ट स्कूलों में लोकप्रिय हुई ही है, इसके अलावा 'द साउण्ड आफ म्यूजिक इन राजस्थान' तथा 'फॉकवेज इन राजस्थान' की लोकप्रियता में पेंढारकर के जीवंत स्केचों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने राजस्थान की अनूठी कला पत्रिका 'मिस्लेनी' का भी नौ वर्षों (१९५७-६५) तक कुशल सम्पादन किया। आजकल वे दो किताबों की तैयारी में व्यस्त हैं, इनमें से एक 'मेमोरी ड्राइंग' होगी, जिसमें कला में आटोबायोग्राफी जैसा प्रयोग होगा, दूसरी जयपुर की स्थापत्य व शिल्प के मूल तत्वों पर आधारित होगी।

इसके अलावा भी पेंढारकर कार्टूनिस्ट के रूप में खूब छपे हैं तथा पाठ्य पुस्तक मंडल तथा जनगणना विभाग को अपनी सेवाएं दी हैं। अपने प्रारम्भिक दिनों में पेंढारकर ने बोर्ड पोतने से लेकर अछूतों व अपंगों के स्कूलों तक में काम किया है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को नजदीक से देखने में उन्हें आनन्द आता है। पर वे कला के विकास में अकादमियों की भूमिका को स्वीकार नहीं करते, वे उन्हें पुरस्कार बांटने की सरकारी दुकान कहते हैं—वे कहते हैं, "कलाकार का यह काम नहीं होता कि वह अकादमी के पीछे पड़े, उसके चक्कर लगाये। अकादमी में जो लोग बैठे हैं, उन्हें कला की तमीज ही नहीं है।"

वे आरोप लगाते हैं, "अकादमी में प्रदर्शनियों के लिए कमेटी तक नहीं है। सचिव निर्णायकों को पहले से ही अपना निर्णय सुना देते हैं।"

वे माडर्न आर्ट को लगभग नकारते हुए कहते हैं—जो कुछ आंखों से सामने दिख रहा है, अगर कोई उसे ज्यों का त्यों कैनवास पर नहीं उतार सकता, तो उसे अपने को कलाकार कहना बेकार है। माडर्न आर्ट का यह मतलब तो नहीं कि आप कुछ भी बनाकर बिना टाइटल के लटका दीजिए और समीक्षक उसका चाहे जो अर्थ लगा ले।

पेंढारकर कहते हैं, "मकबूल फिदा हुसैन कलाकारों में बड़ा नाम हो सकते हैं, पर वे बड़े कलाकार नहीं हैं। उनसे बड़ा कलाकार तो मैं कार्टूनिस्ट लक्ष्मण को मानता हूं, जो रोज नया कार्टून रचते हैं और आज तक रिपीटीशन नहीं हुआ। हुसैन को तो मैं कार्टूनिस्ट भी नहीं मानता।"

पेंढारकर को राजस्थान के रेगिस्तान से ज्यादा पेड़, लोककला, प्राच्य अवशेष आकर्षित करते हैं। उन्हें चिन्ता है कि यह सब धीरे-धीरे खतम होता जा रहा है। वे कहते हैं, "थोड़े दिन बाद जयपुर में भी पुरानी इमारतें नहीं होंगी, यह शिल्प, स्थापत्य नहीं होगा, बस चौड़ी कंकरीट की सड़कें होंगी और बहुमंजिला इमारतें होंगी। पहले जिन आदिवासी इलाकों में उनके रहन-सहन में लोकतत्व दिखायी देता था, अब वहां भी टेरीकाट के कपड़े दिखायी देते हैं।"

रवि चतुर्वेदी

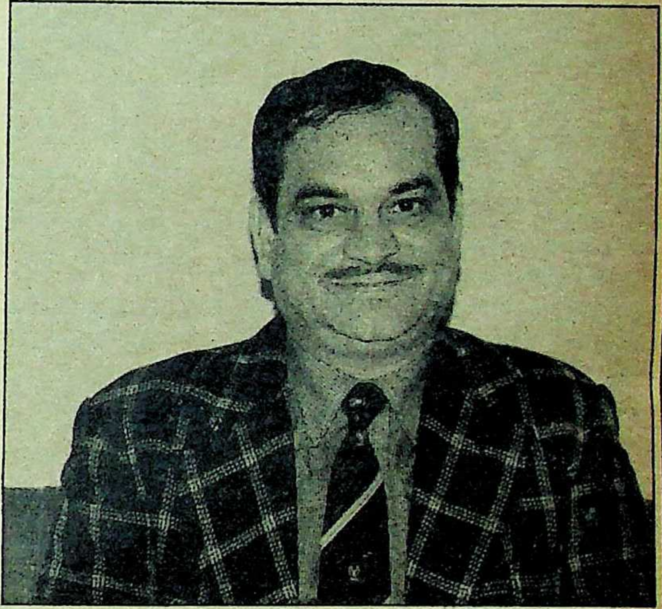

"दूसरे देशों की बात दूसरी है, पर भारत में क्रिकेट की कमेंट्री अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में ज्यादा पसंद की जाती है।" यह अनुभव है उस अध्यापक का जिसने पिछली ८ फरवरी को अपने कमेंटेटर कैरियर के २५ साल पूरे कर लिये।

रवि चतुर्वेदी ने ८ फरवरी, १९६४ को इंग्लैंड के विरुद्ध फीरोजशाह कोटला में कमेंटेटर के रूप में खेल-क्षेत्र में कदम रखा था। तब से अब तक वे ४० टेस्ट और १० एकदिवसीय मैचों का आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण कर चुके हैं। इनमें आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका एवं वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट एवं एकदिवसीय मैच भी शामिल हैं। इसके अलावा वे १९७६ में वेस्ट-इंडीज, १९८० में आस्ट्रेलिया और १९८१ में न्यूजीलैंड से टेस्ट शृंखलाओं का भी प्रसारण कर चुके हैं। न्यूजीलैंड टीवी ने १९८१ के दौरे पर उनकी सेवाएं अतिथि कमेंटेटर के रूप में लीं। उधर १९७६ में कैरेबियन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन (सीबीसी) ने भी अतिथि कमेंटेटर के रूप में उनसे अंग्रेजी में कमेंट्री करवायी।

रवि हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के प्रमुख नायक हैं। आज हिंदी क्रिकेट कमेंट्री में जिस शब्दावली का उपयोग हो रहा है, उसके विकास व प्रयोग में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। अब तक उन्होंने क्रिकेट पर पांच पुस्तकें (तीन अंग्रेजी व दो हिंदी) लिखीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कालेज में प्राणिशास्त्र विभाग में वे पिछले २५ वर्षों से पढ़ा रहे हैं। उनकी शिक्षा दिल्ली, चेकोस्लोवाकिया और कनाडा में हुई। अपने विद्यार्थी जीवन में वे विश्वविद्यालय स्तरीय क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। ■

गोरख पांडेय

सामाजिक परिवर्तन का स्वप्न देखनेवाले भावुक और संवेदनशील कवि गोरख पांडेय ने विगत २८ जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नर्मदा हास्टल के अपने कमरे (४१५ नंबर) में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उनके लटकते शव के नीचे जो पर्चा पाया गया, उस पर लिखा था कि 'मैं अपनी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। इसके लिए किसी को तंग न किया जाये।'

देवरिया जिले के मुंडेरवा शाहजहांपुर गांव में १९४५ में जन्मे गोरख को जनकवि के रूप में ज्यादा जाना जाता था। 'समाजवाद बबुआ धीरे-धीरे आयी' वाला उनका भोजपुरी गीत बेहद मशहूर हुआ था। वे खड़ी बोली के भी अच्छे कवि थे। कुर्सीनामा, कानून, फूल और उम्मीद आदि उनकी कविताएं काफी लोकप्रिय हुई थीं। राधाकृष्ण प्रकाशन से उनका जो कविता संग्रह 'जागते रहो सोने वालों' नाम से १९८३ में प्रकाशित हुआ था, उस पर उन्हें 'ओम प्रकाश साहित्य सम्मान' दिया गया था।

सत्तर के दशक के आरंभ में नक्सलबाड़ी किसान संघर्ष के साथ ही पूरे देश में फैले किसान आंदोलन से वे इतने प्रभावित हुए थे कि आंदोलनकारियों के लिए प्रेरक गीत लिखने लगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में जन आंदोलनों में उनके गीत खूब लोकप्रिय हुए। कविता, दर्शन और राजनीति से गहरे जुड़े गोरख पांडेय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दर्शन में एमए करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से 'ज्यां पाल सात्र के अस्तित्ववाद में अलगाव के तंतुओं' पर शोधकार्य किया था और बाद में वहीं शोध सहायक (रिसर्च एसोशिएट) हो गये थे।

नासिर फैयाजुद्दीन डागर

प्रख्यात ध्रुपद गायक, डागर बंधुओं में एक उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर का पिछली ७ फरवरी को सबेरे रियाज करते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। १९३४ में इंदौर में जन्मे नासिर ने ध्रुपद की दीक्षा अपने पिता उस्ताद नसीरुद्दीन खान डागर और उनके बड़े भाइयों उस्ताद नासिर मुईनुद्दीन डागर व नासिर अमीनुद्दीन डागर से ली। अपने बड़े भाई उस्ताद जहीरुद्दीन डागर के साथ उन्होंने डागरबंदी ध्रुपद की जुगलबंदी परंपरा को आगे बढ़ाया। मौसिकी की ध्रुपद शैली के मूल रूप को संरक्षित रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनके ध्रुपद अंग की गायिकी में गहरा भक्तिभाव था। वे मंत्रोच्चार के साथ आलाप करते थे। उनका हर ध्रुपद किसी-न-किसी देवता की भक्ति में निवेदित था। उनमें लयकारी का चमत्कार नहीं, मधुरता और समर्पण था।

उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान मिले तथा अपने बड़े भाई उस्ताद जहीरुद्दीन डागर के साथ उन्होंने विदेशों में आयोजित होने वाले भारत महोत्सवों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। मशहूर कथक नर्तक बिरजू महाराज ने फैयाजुद्दीन डागर केनिधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है, "डागरवाणी में डागर बंधुओं की जो माला है, उसकी महत्वपूर्ण कड़ी टूट गयी है।" उस्ताद अमजद अली ने अफसोस जताते हुए कहा, "यह अजूबा है कि डागर बंधुओं की जोड़ी में मुईनुद्दीन चले गये और अब दूसरी जोड़ी में फैयाजुद्दीन भी चले गये। ध्रुपद को लोकप्रिय बनाने में इन दोनों का भारी योगदान है। अब अधूरापन आ गया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए सुकून मिलता है कि फैयाज का बेटा ध्रुपद का होनहार गायक है।"

मशहूर कथक नर्तक बिरजू महाराज ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है, "डागरवाणी में डागर बंधुओं की जो माला है, उसकी महत्वपूर्ण कड़ी टूट गयी है।"

पं० नरेंद्र शर्मा

मानव-मन की कोमल अनुभूतियों को वाणी देने वाले छायावादोत्तर काल के प्रगतिशील कवि एवं फिल्मी गीतकार नरेंद्र शर्मा ११ फरवरी को नहीं रहे।

बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में १९१३ में एक खाते-पीते ब्राह्मण परिवार में जन्मे नरेंद्र शर्मा बचपन से ही साहित्यिक रुचि के थे, वे प्रयाग विश्वविद्यालय के एमए थे। उनकी कविताओं की असली धूम छायावाद काल के बाद मची। वे पहले अपनी देशभक्तिपरक कविताओं के लिए प्रसिद्ध हुए, बाद में वे फिल्मी दुनिया से संबद्ध हो गये। उन्होंने फिल्मी गीतों के अलावा सैकड़ों फिल्मों की कथा और पटकथा तो लिखी ही, उनकी कविता, गद्य और नाटकों की लगभग बीसों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 'प्रवासी के गीत' और पलाशवन' समधिक प्रसिद्ध हैं। पं० नरेंद्र शर्मा स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, पं० जवाहरलाल नेहरू के पांच वर्षों तक निजी सचिव भी रहे।

उन्होंने फिल्मी गीतों को साहित्यिक संस्पर्श दिया। उनके फिल्मी गीतों में 'ज्योति कलश छलके' के अलावा 'नैन दीवाने, इक नहीं माने, करे मनमानी सजना' और 'राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला' विशेष लोकप्रिय रहे। बाम्बे टाकीज की फिल्म 'ज्वार भाटा' के लिए नरेंद्र शर्मा के गीत फिल्मी गीतों के क्षेत्र में एक उपलब्धि माने जाते हैं। वे वर्षों तक विविध भारती से तो संबद्ध रहे ही, विविध भारती के 'छाया गीत', 'चित्रहार' और 'हवा महल' जैसे कार्यक्रम उन्हीं की देन हैं। अनेक सरकारी-सामाजिक समारोहों के लिए भी उन्होंने गीत बनाये जिनमें दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का उद्घाटन गीत 'शुभ स्वागतम्' प्रमुख माना जाता है। पं० नरेंद्र शर्मा ने इधर जब से 'महाभारत' की कथा व गीत लिखे, तब से ज्यादा चर्चा में थे। —डा० मुश्ताक अली

नरेंद्र शर्मा के फिल्मी गीतों में 'ज्योति कलश छलके' के अलावा 'नैन दीवाने, इक नहीं माने, करे मनमानी सजना' और 'राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला' विशेष लोकप्रिय रहे।

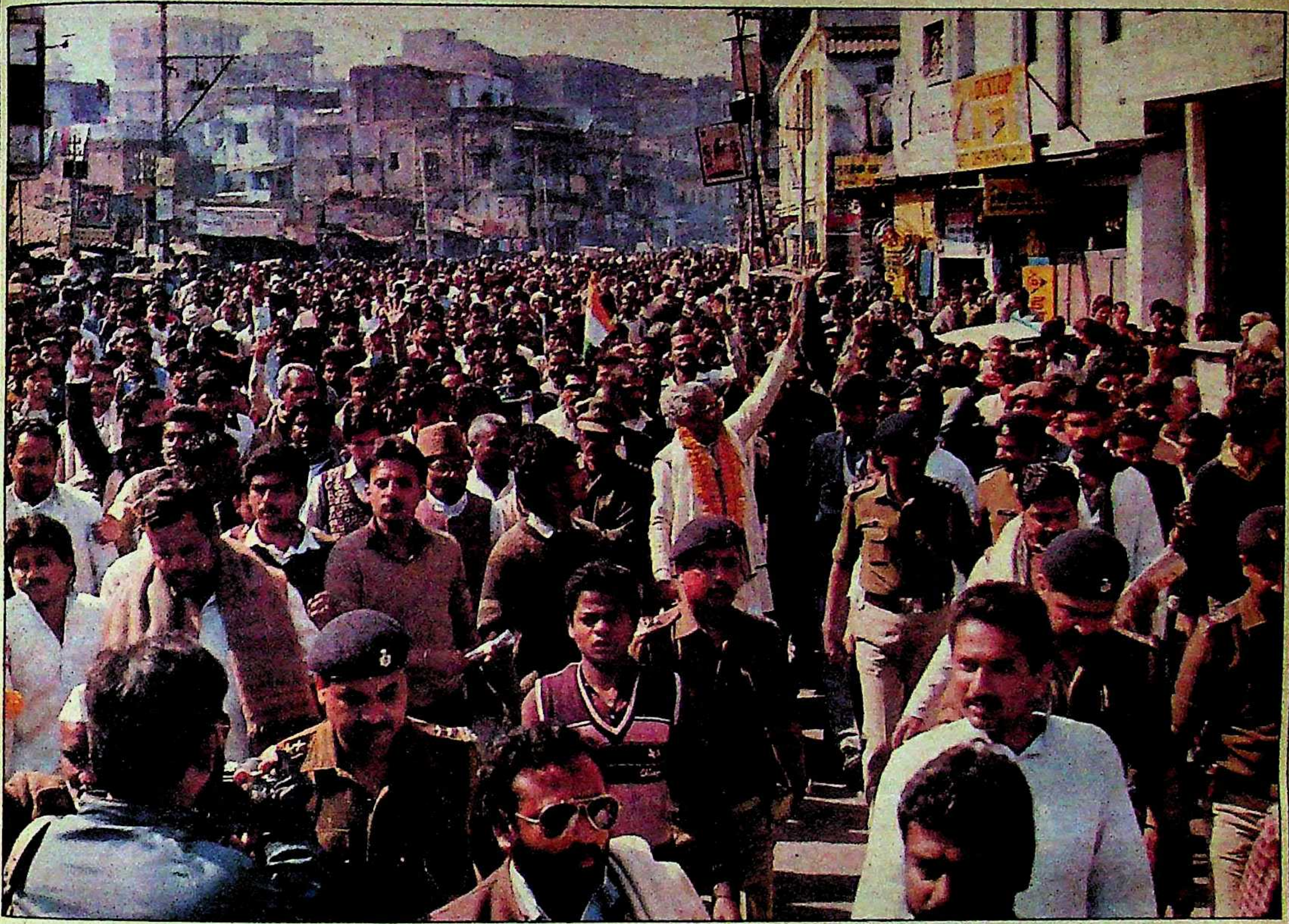

आजाद की पदयात्रा

कुरसी बचाने की खातिर

विद्रोह के भंवर में
डूबती-उतराती अपनी नौका को
बचाने के लिए
मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने
पदयात्रा के तिनके का सहारा भी लिया।
मुख्यमंत्री ने
यह पखवाड़ा कैसे छटपटाते
हुए काटा ?

मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह का सितारा डूबने के बाद सबसे ज्यादा खतरे में यदि कोई मुख्यमंत्री थे, तो वे बिहार के भागवत झा आजाद ही थे। लेकिन उन्होंने विक्षुब्ध विधायकों से मिलना गवारा नहीं किया, जबकि आजाद को हटाने या न हटाने के सवाल पर राजीव गांधी ने बिहार राजनीति के बरगद से लेकर घास जैसी हैसियत रखनेवाले नेताओं से भी परामर्श किया। राजीव गांधी के खास सलाहकारों, बूटा सिंह और माखनलाल फोतेदार, के मतभेद आजाद का कवच बन गये थे और इसी मतभेद ने असंतुष्टों की मुहिम में नयी जान भी फूंकी, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजव गांधी दुविधाग्रस्त हो गये। आजाद को हटाने से तौहीन होने का भय उन्हें दिखाया गया, तो न हटाने पर बिहार कांग्रेस के टुकड़े-टुकड़े हो जाने का खतरा उनके सामने खड़ा किया गया। उन्हें विक्षुब्धों ने यह धमकी तक दे डाली थी कि यदि आजाद हटाये नहीं गये, तो २१ फरवरी से शुरू होनेवाले संसद के बजट सत्र के समय विक्षुब्ध दिल्ली में हंगामा करेंगे। विक्षुब्धों ने २ फरवरी को अपनी ताकत भी दिखा दी। उस दिन विधानमंडल का सत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया और राजीव गांधी को मजबूर होकर बिहार के इस राजनीतिक संकट को हल करने के लिए चार सदस्यों (बिंदेश्वरी दुबे, ललितेश्वर प्रसाद शाही, बिहार इंका अध्यक्ष तारिक अनवर और डा० जगन्नाथ मिश्र) की शांति समिति गठित करनी पड़ी।

ऐसी स्थिति में आजाद समर्थक केंद्रीय लाबी ने आजाद को मशविरा दिया कि एकमात्र जनशक्ति के बल पर वे टिके हुए हैं, अतः अपनी जनशक्ति का

उन्हें प्रदर्शन भी करना चाहिए। लिहाजा कुरसी बचाने की छटपटाहट ने मुख्यमंत्री आजाद को पटना की सड़कों पर पदयात्रा करने के लिए मजबूर कर दिया। वह दृश्य अद्भुत था—प्रांत की सत्ता का मुखिया राजधानी पटना की सड़कों पर जनसमर्थन का जायजा लेने के लिए घूम रहा था। हजारों की भीड़ आजाद के पीछे थी। आजाद विधायकों के पास हाथ जोड़ने कभी नहीं गये, लेकिन आम जनता के बीच हाथ जोड़े घूम रहे थे। पदयात्रा में आजाद के समर्थक विक्षुब्धों पर कटाक्ष करते हुए नारे लगा रहे थे, “जो बिहार को लूटा है, वही आजाद से रूठा है।”

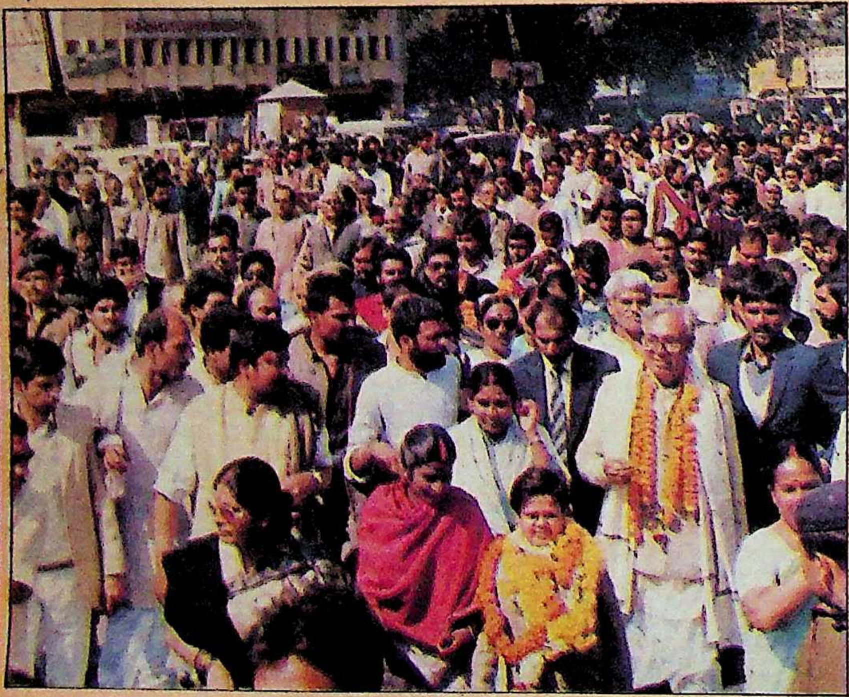

वह दृश्य अद्भुत था—
प्रांत की सत्ता का मुखिया राजधानी
पटना की सड़कों पर
जनसमर्थन का जायजा लेने के लिए घूम रहा
था। हजारों की भीड़
आजाद के पीछे थी। आजाद विधायकों के पास
हाथ जोड़ने कभी नहीं गये,
लेकिन आम जनता के बीच हाथ जोड़े घूम रहे
थे। पदयात्रा में
आजाद के समर्थक विक्षुब्धों पर
कटाक्ष करते हुए नारे लगा रहे थे,
“जो बिहार को लूटा है, वही आजाद से
रूठा है।”

आजाद की इस हलचल से विक्षुब्ध फिर सक्रिय हो उठे। ५ फरवरी को डा० जगन्नाथ मिश्र व तारिक अनवर दिल्ली पहुंचे, क्योंकि अगले दिन ही राजीव गांधी राजस्थान की यात्रा पर निकलने वाले थे। उस दिन इन नेताओं ने दिल्ली में क्या किया, इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि ६ फरवरी से दिल्ली में बिहार की राजनीति का खाता फिर से उलटा जाना शुरू हो गया। शांति समिति के बिंदेश्वरी दुबे भी उस दिन दिल्ली में थे, लेकिन केंद्रीय राज्यमंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही दिल्ली से बाहर थे। उसी दिन शांति मिशन के तीन सदस्यों, दुबे, तारिक अनवर और डा० मिश्र ने माखनलाल फोतेदार और इंका महासचिव गुलाम नबी आजाद से बातें कीं। इधर बिहार के मामले में दिल्ली की फिजा गर्म हुई, तो पटना में जमें आजाद ने एक बार फिर अपने जन-समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए पदयात्रा का मन बना लिया। ७ फरवरी को आजाद ने पटना की सड़कों पर एक बार फिर लंबी पदयात्रा की। इस दिन भी उनके साथ हजारों की भीड़ थी। उस दिन उन्होंने अपने भाषण में कहा, “जनता का बल माफिया के बल से बड़ा होता है, मेरी सरकार को माफिया के लोग नहीं गिरा सकते।” अगले दिन ८ फरवरी को आजाद मुख्यमंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे तो फिर उन्हें लगा कि उनकी सत्ता पर आंच आ सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से राजीव गांधी ने कहा था कि बिहार, गुजरात, राजस्थान आदि के बारे में शीघ्र फैसला लिया जायेगा। राजीव गांधी की इस टिप्पणी से न केवल विक्षुब्ध उत्साहित हुए, बल्कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इसकी जोड़-तोड़ भी शुरू हो गयी।

एक तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री शाही युद्ध स्तर पर अपनी उम्मीदवारी को लेकर लाबिंग में जुटे थे, तो दूसरी तरफ डा० जगन्नाथ मिश्र भी नये उत्साह से अपनी खोई गद्दी वापस पाने के प्रयास में लग गये। राजीव गांधी के लखनऊ के इंका महाधिवेशन से दिल्ली लौटने पर १० फरवरी को बिहार का मामला फिर गरमाया। राजीव गांधी ने उस दिन शाम साढ़े चार बजे बिंदेश्वरी दुबे को तलब किया, फिर छह बजे अब्दुल गफूर से बातचीत की। इसी दिन राजीव सत्येंद्र नारायण सिंह, बलिराम भगत, एलपी शाही और जगन्नाथ मिश्र से भी मिले। १० फरवरी को ही आलाकमान के बुलावे पर पूर्व विधानसभाध्यक्ष शिवचंद्र झा भी दिल्ली पहुंच चुके थे।

अपनी मुलाकात में सत्येंद्र नारायण सिंह ने राजीव गांधी से दो टूक शब्दों में कहा कि दबाव में नेतृत्व परिवर्तन करना कतई उचित नहीं होगा। उसी रोज रात में मुख्यमंत्री आजाद की भी लंबी बातचीत प्रधानमंत्री से हुई, पर उन्हें भी 'निगेटिव' संकेत नहीं दिया गया। १२ फरवरी को, जिस दिन बिहार में आजाद की सरकार के एक साल पूरे हो रहे थे, आजाद दिल्ली में ही थे। इधर विक्षुब्धों ने यह ऐलान कर रखा था कि आजाद की १३ फरवरी को छुट्टी हो जायेगी। वैसे भी १३ का अंक बिहार के मुख्यमंत्रियों के लिए अशुभ माना जाता है। जगन्नाथ मिश्र (१३ अगस्त, १९८३), चंद्रशेखर सिंह (१३ मार्च, १९८५), बिंदेश्वरी दुबे (१३ फरवरी, १९८८) के सत्ता के सितारे १३ तारीख को ही डूबे थे। लेकिन १३ फरवरी को आजाद का पत्ता साफ नहीं हुआ। उस दिन आजाद समर्थक विधायकों और सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सांसद कुंवर राम को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन करके इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दी जायेगी। इस आश्वासन के बाद आजाद दूने उत्साह से १४ फरवरी को पटना वापस आये तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अब वे असंतुष्टों से भी बात करेंगे। सत्ता पर आये संकट को टालने के लिए आजाद ने यह पखवाड़ा किस छटपटाहट में व्यतीत किया, इसे वे ही जानते हैं।

जहां मुख्यमंत्री विधायकों के बहुमत से न चुने जाकर आलाकमान के फरमान से थोपे जायेंगे, वहां कोई मुख्यमंत्री चैन से कैसे रह सकता है। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की यही नियति है। **—विकास झा**

'महाभारत' का महाभारत

आजकल टीवी सीरियलों में 'महाभारत' बेहद लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन उसकी लोकप्रियता के साथ-साथ उसकी कथा, उसकी भाषा एवं उसकी ऐतिहासिकता पर कुछ संदिग्धता भी व्यक्त की जा रही है। महाभारत पर जो सवाल उठाये जा रहे हैं, आखिर उनमें कितना दम है?

"हमें इस बात का आभास था कि 'महाभारत' के प्रदर्शन के बाद बहुत सारे विवाद तथा प्रश्न उठ खडे होंगे और लोग विभिन्न तथ्यों-प्रकरणों को सामने रखते हुए 'महाभारत' सीरियल में वर्णित घटनाओं को तथ्यहीन बतलायेंगे और आलोचना करेंगे।" 'महाभारत' सीरियल के निर्माता-निर्देशक बीआर चोपड़ा ने 'माया' को बतलाया, "बहुत सारे टीकाकारों ने 'महाभारत' की अलग-अलग ढंग से टीकाएं लिखीं हैं, नये-नये साक्ष्य पेश किये हैं। बहुत-सी ऐसी टीकाएं तथा साक्ष्य हैं जो एक ही प्रकरण में परस्परविरोधी हैं, फिर महाभारत की कथा दो-चार सौ वर्ष पुरानी नहीं, बल्कि काफी पुरानी है। वह एक इतिहास है, जहां से उस 'भारत वर्ष' की शुरुआत होती है जिसका नामकरण दुष्यंत-शकुंतला-पुत्र महाराज भरत के नाम पर हुआ था। हमने महाभारत के तमाम टीकाकारों की कृतियों का अध्ययन किया और अंततः इस नतीजे पर पहुंचे कि सीरियल की पटकथा के लिए पुणे स्थित भंडारकर ओरियंट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित तथा डा॰ वीएस सुखणकर द्वारा संपादित 'महाभारत' को आधार बनाया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ने लगभग ५० वर्षों तक महाभारत के बारे में विशद शोध कर जो ग्रंथ तैयार किया था, हमारे विचार से वह ज्यादा प्रामाणिक रहा।"

लेकिन संस्कृत तथा प्राचीन संस्कृति के प्रख्यात विद्वान प्रो॰ वासुदेव व्यास ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार, "रामकृष्ण भंडारकर ने अपने दीर्घकालीन शोध के बाद यह प्रमाणित किया था कि भारत में कृष्णभक्ति का प्रचार ईसाइयों के भारत-आगमन के बाद ही हुआ था—परमेश्वर को कृष्ण का नाम भी क्राइस्ट या खीस्त की नकल पर दिया गया था। इस भंडारकर इंस्टीट्यूट ने अपने यहां से प्रकाशित 'महाभारत' में बिना कोई ठोस प्रमाण दिये महर्षि वेदव्यास कृत 'महाभारत' में वर्णित तमाम श्लोकों एवं अध्यायों को क्षेपक घोषित कर दिया, जिन्हें प्रख्यात आचार्यों एवं टीकाकारों ने प्रामाणिक माना था।"

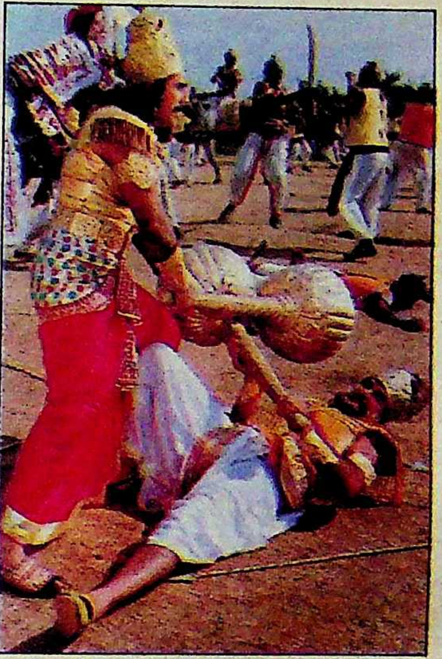

दुर्योधन की भूमिका में पुनीत इस्सर

विवाद से शुरुआत: 'महाभारत' का प्रथम एपीसोड तथा सूत्रधार (हरीश भिमानी) द्वारा 'समय' के माध्यम से कहे गये संवाद 'दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा' तथा 'महाराज भरत ने अपने नौ पुत्रों को राजकार्य के अयोग्य एवं अक्षम पाकर प्रजा के बीच से उपमन्यु (भूमन्यु) का चुनाव कर जिस लोकतांत्रिक शासन पद्धति की नींव डाली थी, उसे उपमन्यु की १३वीं पीढ़ी में जन्मे महाराज शांतनु ने खतम कर दिया' से विवाद की शुरुआत हुई। प्रो॰ वासुदेव व्यास का मानना है कि महर्षि वेदव्यास रचित दूसरे पुराणों में वर्णित है कि 'अजनामवर्ष' या 'हिमवर्द्धष' के नाम से प्रख्यात आर्यावर्त का नाम महाराजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा था न कि शकुंतला एवं दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। फिर शकुंतला-दुष्यंत-पुत्र भरत महाराजा ऋषभदेव के पुत्र भरत से लगभग २० पीढ़ी के बाद पैदा हुए थे।

प्राचीन, संस्कृति, धर्म एवं इतिहास के मान्य विद्वान प्रो॰ अनंत देव भी महाराजा भरत से लोकतांत्रिक या प्रजातंत्रीय शासन पद्धति की शुरुआत का विरोध करते हैं। उन्होंने 'माया' को बतलाया, "प्रो॰ वासुदेव व्यास की टिप्पणी सही है कि भारतवर्ष का नामकरण ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हुआ था, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने

यशोदा और कृष्ण की भूमिका में मंजु व्यास और शंपा गोपीकृष्ण

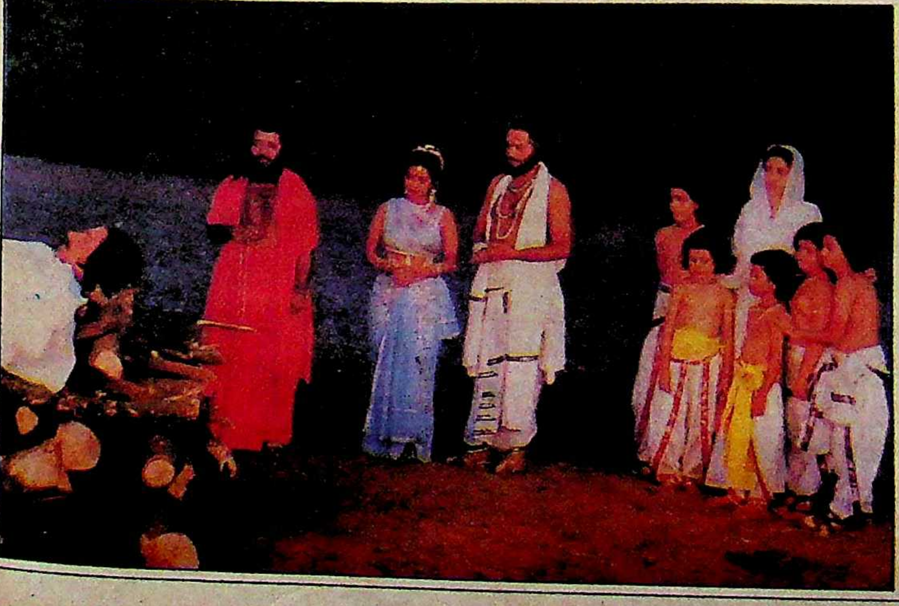

राजा पांडु के दाह-संस्कार के समय
कुंती और पांडु-पुत्र

आओ मिलकर हम 'घर-घर' खेलें !

home landscaping

जब जीवन भर की पूंजी लगायेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिये अपनी निशानी भी तो छोड़ कर जायेंगे।

जी हां! आखिर जीवन भर की पूंजी लगाकर जब अपना घर बनायेंगे तो किसी भी चीज़ में समझौते का सवाल ही नहीं उठता। खासकर सीमेन्ट का चुनाव तो बहुत ही सोच समझकर कीजियेगा।

फिर सबसे बेहतर सीमेन्ट की सही पहचान तो किसी अच्छे बिल्डर को ही हो सकती है, है ना? तो भारत के नं. 1 बिल्डर जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के वर्षों के अनुभव का फायदा अब आप भी उठाइये। जिस सीमेन्ट से वे बड़े-बड़े पुल और बांध देश-विदेश में बनाते हैं, उसी भरोसेमन्द सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट से आप भी अपना घर बनवाइये।

सीमेन्ट की क्वालिटी का मापदण्ड हमेशा उसमें उपयोग किये गये चूना-पत्थर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इसीलिये सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट का कारखाना देश के सबसे बेहतरीन चूना-पत्थर की खदानों में पास स्थित है। साथ ही साथ सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट अत्याधुनिक कम्प्यूटर युक्त तकनीक से बनाया जाता है।

तभी तो सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट में है बेजोड़ पकड़, लाजवाब मजबूती और बेमिसाल भरोसा।

जब भारत के नं. 1 बिल्डर के अनुभवों से बना सीमेन्ट उपलब्ध है, तो फिर भला किसी और सीमेन्ट को क्यों खरीदें?

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट : इसे नाम से मांगिये।

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट की गारंटी
- तुरन्त मज़बूत पकड़
- 28 दिनों के बदले सिर्फ 3 दिनों में 330 kg/cm² की कम्प्रेसिव मज़बूती।
- हर बोरी में पूरा वज़न — पूरे 50 किलो।

GUARANTEED QUALITY

मज़बूत रहे यह बंधन-जीवनभर

सुपरप्लस
जेपी
सीमेन्ट

मास्टर बिल्डर

जयप्रकाश इन्डस्ट्रीज़ का एक उत्कृष्ट उत्पादन

LINTAS (DELHI) JI 58 2621 Hi

महाभारत के द्रोणाचार्य

‘महाभारत’ सीरियल में कितनी विसंगतियां हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, इसकी पर्तें इसके एपीसोडों के प्रदर्शन के साथ ही प्याज के छिलके की तरह पर्त-दर-पर्त उभरती रहेंगी।

शकुंतला-दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हुए नामकरण को ही न केवल माना, बल्कि प्रचारित भी किया, इसलिए आम तौर पर लोगबाग इसे ही सही मानते हैं। रही भारत में लोकतंत्र शासनपद्धति की बात, तो वह महाराजा दुष्यंत के बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, इसका उल्लेख पुराणों तथा दूसरे प्राचीन ग्रंथों में भी है। फिर जब चोपड़ा ‘महाभारत’ के महत्वपूर्ण पात्रों को पेश कर रहे थे, तो उन्हें महाराज भरत के बाद महाराज हस्ति (महाराज भरत द्वारा चुने गये महाराजा उपमन्यु/भूमन्यु के पौत्र) के काल का उल्लेख अवश्य करना चाहिए था। उन्होंने ही हस्तिनापुर का अंततः निर्माण कराया था, कौरवों के समय तक उनके साम्राज्य की वही राजधानी रही। सीरियल में हस्तिनापुर को राजधानी बनाने के प्रकरण के आवश्यक तथ्यों को खोज कर जरूर फिल्माना चाहिए था, क्योंकि यही हस्तिनापुर भारत की राजधानी का निर्माण-सूत्र बना था। चोपड़ा यह कहकर नहीं टाल सकते कि पूरे सीरियल को ५२ एपीसोडों में समेटना था, अतएव ऐसे (महत्वपूर्ण) प्रसंगों को उन्होंने छोड़ दिया था। कंस, देवकी-वसुदेव के जेल-प्रसंग तथा कृष्ण के माखन-प्रसंगों को उन्होंने आवश्यकता से बहुत अधिक खींचा है।”

अपनी सफाई में: इसकी चर्चा चलने पर बीआर चोपड़ा बतलाते हैं, “महाभारत की कथा विशद है। अगर मुझे ५२ के बजाय १०४ एपीसोड एक-एक घंटे के मिले होते, तो मैं बहुत सारे प्रकरणों को बड़े प्रभावशाली ढंग से फिल्माता। हस्तिनापुर जैसे बहुत सारे प्रकरण हैं, जो हमारे प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। रही बात कंस, देवकी-वसुदेव तथा कृष्ण लीलाओं के प्रसंग की, तो मैंने उन प्रसंगों को बहुत संक्षिप्त कर फिल्माया है। हमने शुरू के नौ एपीसीडों में ‘महाभारत’ की पृष्ठभूमि को—महाराज भरत से लेकर महारानी माद्री तथा कुंती द्वारा विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद से पुत्र-प्राप्ति प्रकरण को फिल्माया था। रही बात भरत द्वारा स्थापित तथा महाराजा शांतनु द्वारा लोकतंत्र को खतम कर राजवंश परंपरा की शुरुआत करने की घटना की, तो यह तो इतिहास है, उसे आप झुठला कैसे सकते हैं भला? मैंने सूत्रधार और समय के माध्यम से इस बात को कहलवाया भी है।”

लोकतंत्र के खातमे तथा राजवंशशाही की पुनः स्थापना के बारे में बीआर चोपड़ा सीधे कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन उनका मानना है कि अगर शांतनु ने मत्स्य राजपुत्री सत्यवती से विवाह करने के बावजूद शासक का चुनाव राजवंश के बजाय लोकतांत्रिक पद्धति से आम लोगों के बीच किया होता, तो उस नियोग-विधि को अपनी दोनों पुत्रवधुओं (अंबिका एवं अंबालिका) पर आजमाकर संतानोत्पत्ति की जरूरत नहीं पड़ी होती—खुद सत्यवती ने पुत्रवधुओं के साथ नियोग के लिए जिस पुरुष (महर्षि व्यास) को चुना था, वह भी विवाह [illegible] एक ऋषि से संपर्कों का परिणाम था। नियोग का इसी विधि को पांडु की दोनों महारानियों (कुंती एवं माद्री) ने भी आगे चल कर वंश-रक्षा के लिए अपनाया और पांडवों का जन्म हुआ। सत्यवती की ही तरह कुंती अविवाहिता अवस्था में कर्ण का मातृत्व-सुख भोग चुकी थी। लोकतांत्रिक परंपरा के हनन तथा राजवंश को जीवित रखने की जिजीविषा ने ही ‘महाभारत’ का सृजन किया था।

कुछ विद्वानों ने गंगा के मुख से कहलवाये गये ‘जन्म की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है’ संवाद पर भी विवाद उठा कर वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था का उदाहरण दिया। महाभारत में एक तरफ भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर जैसे क्षत्रिय हुए जिन्होंने क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा कर्म से ब्राह्मणत्व धर्म का पालन किया, लेकिन वे क्षत्रिय ही कहलाये। दूसरी तरफ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा सारी जिंदगी शस्त्र-पूजा से जुड़े रहने के बावजूद ब्राह्मण ही कहलाये। इस विवाद की गहराई में ज्यादा पैठने के बजाय चोपड़ा सिर्फ इतना कहते हैं, “इस हिसाब से भी तो हम ठीक हैं। भीष्म, युधिष्ठिर तथा विदुर की महत्ता सिर्फ उनके कर्मों के कारण बढ़ी। इसीलिए वे अपने खानदान में धनुर्धारी के बजाय महात्मा और आदर्श पुरुष के रूप में ज्यादा प्रतिष्ठित हुए।”

एक और आपत्ति: ‘महाभारत’ के एक और प्रकांड पंडित चंका सोनावणे की आपत्ति थी कि महाराज भरत ने प्रजाजनों के बीच से किसी को चुनकर महाराजा नहीं नियुक्त किया था, न ही काशिराज ने स्वयंवर में हस्तिनापुर को नजरअंदाज किया था, उन्होंने हस्तिनापुर नरेश को भी आमंत्रण-पत्र वैसे ही भेजा था, जैसे दूसरे राजाओं को। दूसरे एपीसोड में वर्णित राजा शाल्व से भीष्म की दो बार मुठभेड़ (एक बार घुड़सवारी करते समय दूसरी बार अंबा, अंबिका, अंबालिका को स्वयंवर के बाद अपहृत कर रथ पर लाते समय) दिखायी गयी है। दोनों घटनाओं के बीच वस्तुतः ६० वर्ष का अंतर है, लेकिन सीरियल में कुछ ही वर्षों का अंतराल है। महर्षि वेदव्यास ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र महाराजा होने का हक खो बैठे थे, न ही जरासंध को कुंती के स्वयंवर में उपस्थित होना बतलाया है। दरअसल, वह कुंती नहीं द्रौपदी के स्वयंवर में आया था और बाद में महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इसी तरह धृतराष्ट्र का यह कहना भी तर्कसंगत नहीं था कि अगर कुंती को पहले संतान पैदा हो गयी, तो साम्राज्य पर शासन करने का अधिकार उनकी संतानें खो बैठेंगी। नियमानुसार शासनाध्यक्ष, चाहे वह बड़ा भाई हो या छोटा, उस की बड़ी संतान ही साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ करती है।

छूटे प्रसंग: कृष्ण-प्रकरण में सीरियल को जहां अनावश्यक वर्णनों के कारण लंबा खींचा गया है, वहीं शकट-कांड, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, भेनकासुर आदि असुरों का कृष्ण द्वारा वध, ब्रह्माजी का मोह-भंग, यमलार्जुन उद्धार जैसे रोचक प्रकरण, जो सीरियल को ऊबाऊ होने से बचा सकते थे, छोड़ दिये हैं। पूतना-वध का प्रकरण भी गलत है। महर्षि व्यास ने साफ कहा है कि पूतना ने भुवनसुंदरी का रूप धारण कर नंदगांव में प्रवेश किया और अष्टमी के दिन जन्मे सारे शिशुओं को दुग्धपान कराकर हत्या की थी। वह अपने रोचक क्रियाकलापों द्वारा गोपिकाओं का मन मोह कर उनका विश्वास अर्जित कर लेती थी। कृष्ण को स्तन पान कराने के लिए यशोदा के सामने ही उनके घर में गयी थी, लेकिन सीरियल में इसे फिल्मी ‘टच’ दे दिया गया।

‘महाभारत’ सीरियल में कितनी विसंगतियां हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, इसकी पर्तें इसके एपीसोडों के प्रदर्शन के साथ ही प्याज के छिलके की तरह पर्त-दर-पर्त उभरती रहेंगी।

—रवींद्र श्रीवास्तव

मैं लोगों की बातों की परवाह नहीं करता !

मतभेदों, विवादों और राजनीतिक पैंतरेबाजियों का शिकार दूरदर्शन धारावाहिक 'महाभारत' आखिरकार प्रसारित हो गया। दर्शक भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन यह धारावाहिक आज भी चर्चा और विवादों का केंद्रबिंदु बना हुआ है। प्रो० वासुदेव वि व्यास, पत्रकार राजेंद्रपुरी सहित कई लोग इस धारावाहिक के निर्माता बलदेवराज चोपड़ा और संवाद व पटकथा लेखक डा० राही मासूम रजा पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ धर्मों के मठाधीशों ने तो डा० राही मासूम रजा को धमकी भरे पत्र भी लिखे हैं कि वे महाभारत लिखना बंद कर दें अन्यथा जान से मार दिये जायेंगे। पर रजा पर इस तरह के आरोपों और धमकी भरे पत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अभी भी अपने काम को उसी ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोग भले ही उनका सिर काट डालें, पर वे 'महाभारत' की स्क्रिप्ट लिखना बंद नहीं करेंगे। 'महाभारत' पर लगे आक्षेपों के संदर्भ में 'माया' ने उनसे लंबी बातचीत की। प्रस्तुत हैं, मुख्य अंश :

माया: आप महाभारत को महाकाव्य मानते हैं। महाकाव्य में तो कई चीजें होती हैं। आप किसे 'प्रिफरेंस' दे रहे हैं? इतिहास, धर्म या राजनीति...किसको?

रजा: *देखिए, इतिहास तो तब था नहीं, जब महाभारत लिखी गयी थी। जिस चीज को आज आप धर्म कहते हैं, वह धर्म भी नहीं था। लेकिन जब श्रीकृष्ण का युग है, तो जाहिर है कि यह कृष्ण-भक्ति तो कृष्ण के बाद ही आयेगी। जिन मानो में हम आज धर्म कहते हैं, वह धर्म नहीं है, लेकिन जब 'नारायण' महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, तो धर्म का होना लाजिमी है। पर धर्म उतना ही होगा, जितना कि महाभारत में है।*

माया: आप लोगों ने 'महाभारत' में कृष्ण के बचपन के अलावा कृष्ण बाल-लीला, कंस-वध वगैरह भी दिखाया, लेकिन यह सब महाभारत में तो है नहीं?

रजा: *महाभारत में कोई भी महत्वपूर्ण करेक्टर ऐसा नहीं है जिसे वेदव्यास ने जन्म से न पकड़ा हो। लेकिन श्रीकृष्ण को ही छोड़ दिया, जबकि वे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।*

माया: महाभारत काल में जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां थीं या जैसा कि 'महाभारत' में है, उसका वर्तमान संदर्भों में राजनीतिक और सामाजिक औचित्य क्या है?

रजा: *'महाभारत' का महत्व यह है कि जो इंडियन पिपुल हैं (मैं यहां पर इंडियन पिपुल कह रहा हूं, हिंदू या मुसलमान नहीं), उनके घरों में 'महाभारत' पढ़ी नहीं गयी। क्योंकि उसमें भक्ति का वह रस नहीं था, जो रामायण में था, इसलिए वह ज्यादा नहीं पढ़ी गयी। महाभारत पढ़ी तो गयी नहीं, लेकिन औरतों ने इसे सुपरस्टीशन (भ्रांति) बना लिया कि वह भाई-भाई के झगड़े की कहानी है, जहां रहेगी वहां झगड़े करायेगी, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दो। जबकि सचाई ठीक उलट है। 'महाभारत' तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी राजनीति का सबसे पहला और सबसे बड़ा डाक्यूमेंट है।*

माया: प्रो० वासुदेव व्यास ने आरोप लगाया है कि आप लोग महाभारत को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं?

रजा: *वे पूर्णरूपेण गलत हैं। उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। वे स्कालर हैं। फिर भी स्कालर गल्तियां कर रहे हैं। यदि स्कालरों ने गल्तियां न की होतीं, तो आज हम उस नरक से न गुजर रहे होते, जिस नरक से गुजर रहे हैं। उन्होंने हमारे इतिहास को भ्रष्ट किया है। उन्होंने लोगों के विचारों को भ्रष्ट किया। लोगों के बीच झगड़े करवाये। धर्म के नाम पर खूनखराबा को बढ़ावा दिया। इस तरह के तथाकथित स्कालरों के कारण ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि स्कालर होने के नाते लोगों के साथ उनकी कुछ जिम्मेदारी भी है। डा० राही मासूम रजा का सिर काट देना आसान काम है। लेकिन यदि आप स्कालर हैं, या फिर झूठ बोलने से बाज आयें। देखिए, मैं इस बात की परवाह ही नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं? मैं तो यह कहता हूं कि महाभारत क्या कहता है? हमारा मूल सोर्स भंडारकर इंस्टीट्यूट की महाभारत है। हम अपने इस सोर्स को छुपा भी नहीं रहे हैं।*

माया: पिछले दिनों प्रसिद्ध पत्रकार राजेंद्र पुरी...?

रजा: *(मेरी बात को बीच में ही काटकर रजा कहते हैं) आलोचकों का हाल तो बहुत बुरा है। राजेंद्र पुरी सीनियर पत्रकार हैं। वे लिखते हैं कि कर्ण छठा पांडव था, उन्हें यही नहीं पता कि कर्ण पांडव नही था। उन्हें एतराज है कि महाभारत देखकर लोग अपनी बीवियों को जुए में दांव पर लगाने लगेंगे। एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया, इससे कास्ट प्राब्लम खड़ी हो जायेगी। एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया गया? अरे, जब आप इम्तहान में बैठे हों और नकल करते पकड़े जायें, तो सजा मिलेगी या नहीं। सजा तो मिलेगी ही। एकलव्य भी दोषी था। उसने चोरी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनायी थी और जो कुछ सीखा, वह चोरी से ही सीखा। अब द्रोण यह तो कह नहीं सकते थे कि तुम तीर मत चलाओ। और कह देते तो क्या देखने जाते कि वह तीर चला रहा है या नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि अंगूठा काट दो, क्योंकि जो ज्ञान तुमने लिया है, उस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। यही कर्ण के साथ भी हुआ। कर्ण ने परशुराम से अपने आपको ब्राह्मण बताया। तो कर्ण ने भी अपराध किया, उसे भी सजा मिली। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। इसमें मोराल्टी तो कहीं इंवाल्व ही नहीं है। दूसरी बात हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने की और आज के जमाने की मोराल्टी में भी काफी फर्क है।*

माया: सुना है, आपको कुछ लोगों ने धमकीभरे पत्र भी भेजे हैं?

रजा: *लोगों का क्या है? वे कहते हैं कि तुम हिंदुत्व का अपमान कर रहे हो, तुम पाकिस्तानी कुत्ते हो। अगर तुमने महाभारत लिखना बंद नहीं किया, तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो क्या मैं मान जाऊं? वास्तव में आज देश की जो स्थिति है, उसे आप देख नहीं रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मुझे इसमें कोई बहुत 'शाक' नहीं लगा। मेरे पास मुसलमानों के भी इस तरह खत आ चुके हैं कई मामलों में कि मार डालूंगा। भाई मार डालिए, मेरा जीना या मेरा न जीना कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। लोगों ने तो महात्मा गाधी को मार डाला, मैं क्या चीज हूं। मुसलमानों, हिंदुओं दोनों ने खत लिखे और कोई पहली बार नहीं लिखा, पहले भी लिखा है और आगे भी लिखेंगे।*

माया: क्या आप लोग इसे ५२ एपीसोडों में पूरा कर सकेंगे?

रजा: *सवाल ही नहीं, मैं इसे खींचना भी नहीं चाहता। लेकिन यह ५२ एपीसोडों में पूरा नहीं हो सकता। हमारी कहानी तो इतनी बड़ी है कि हमें तो इसे काटना पड़ रहा है। ५२ एपीसोडों में यह पूरा नहीं हो सकता, यह बात मैंने पहले ही कह दी थी, लेकिन मंडी हाउस वाले ५२ एपीसोड से ज्यादा दे नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले इसे शुरू हो जाने दीजिए। फिर देख लेंगे। मेरा यह खयाल है कि यह ८० एपीसोडों में पूरा हो जाना चाहिए। हम उन्हीं चीजों को दिखला रहे हैं, जिनका हमारी मेन कहानी से ताल्लुक है।*

—प्रस्तुति : सुषमा त्रिपाठी

सरकार कंगाल होने जा रही है ?

विकासोन्मुख व्यवस्था का तकाजा यह है कि राजस्व-आय में से धन बचाकर विकास-कार्यों में लगाया जाये। लेकिन हमारी सरकार की यह चालू (राजस्व) आय ही २५ प्रतिशत घाटे में चल रही है और वह अंधाधुंध कर्ज लेती जा रही है। हाल यह है कि इस वक्त सरकार पर अरबों रुपए का कर्ज चढ़ गया है और कर्ज का ब्याज तक चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। निश्चय ही यह स्थिति स्वयं सरकार के लिए त्रासद है। पर इस कंगाली के लिए जिम्मेदार कौन है ?

मान लीजिए आप बैंक अधिकारी हैं और आपको प्रति माह ३००० रुपए मिलते हैं। यह पैसा बहुत अधिक तो नहीं है, पर कम भी नहीं है। आप हर महीने बचत या इमरजेंसी खर्च के नाम पर ३०० रुपए निकाल कर अलग रख देते हैं। धीरे-धीरे आपके पास २५००० रुपए जमा हो जाते हैं। आपके दोस्त सलाह देते हैं कि किस तरह आप पलक झपकते इस रकम को दो गुना कर सकते हैं। नतीजतन आप मुर्गीपालन फार्म में यह पैसा लगा देते हैं। शुरू में यदि कमाई शुरू हो गयी, तो आपको लगेगा कि मुर्गियां 'सोने का अंडा' दे रही हैं।

लेकिन मुर्गियों का मिजाज भी बदलता रहता है और कुछ समय बाद आपको अपनी पुरानी स्थिति बनाये रखने के लिए इस धंधे में और पैसा झोंकने की स्थिति आ जाती है। मान लीजिए थोड़े नुकसान की स्थिति में आप परवाह नहीं करते, तो धीरे-धीरे आप अधिक नुकसान उठाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और इसे भरने के लिए यह सोचकर कर्ज लेते जाते हैं कि बाद में सब चुकता हो जायेगा। मान लीजिए यह पैसा भी डूबता जाता है, तो आप अपनी मूल पूंजी खोना शुरू करेंगे और एक दिन आपकी पूंजी खतम हो जायेगी। अब कारोबार कर्ज देनेवाले बैंक के प्रबंधक की दया पर टिका रहेगा। कर्ज बढ़ता जायेगा और यदि धंधा उठा नहीं, तो आपको इसका सूद चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। थक-हार कर एक दिन आप तय करेंगे कि इस धंधे में कोई फायदा नहीं है और आप इसे छोड़ देंगे। नतीजतन आपके मुर्गीपालन फार्म पर बैंक अपना ताला लगा देगा।

बिगड़ती स्थिति : बिलकुल यही पिछले कुछ वर्षों से भारत के साथ हो रहा है। सरकार जानती सब कुछ है, किंतु चुप्पी लगाये हुए है। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अभी भी स्थिति न संभल पाने तक नहीं पहुंची है। किंतु यदि सरकार कुछ ठोस उपाय नहीं करती, तो जल्द ही स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी और सरकार दिवालिया हो जायेगी।

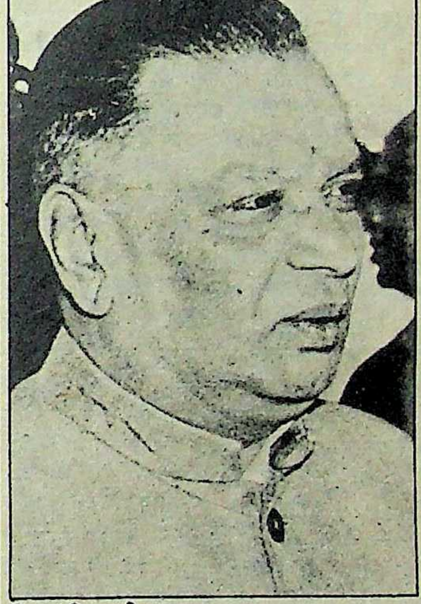

वित्तमंत्री एसबी चह्वाण

अफसोस इस बात का है कि भारत में न कोई कानून है और न राजनेता इस कर्ज का जिक्र करते हैं। इसी महीने केंद्रीय वित्त मंत्री चह्वाण अपना पहला और शायद आखिरी बजट पेश करेंगे और संभावना यही है कि वे कर्ज की चर्चा भी नहीं करेंगे।

१९७९ या उसके आसपास तक सरकारी काम-काज ठीक-ठाक चल रहे थे। स्थिति यह थी कि राजस्व अधिशेष रह जाता था। आप पूछ सकते हैं कि आखिर अधिशेष और राजस्व के मुद्दे को इतना क्यों उछाला जा रहा है ? आखिर पैसा तो पैसा ही है और अगर राजस्व के मद में घाटा तथा पूंजीगत मद में अधिशेष रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ ? सरकार भी यही कहती है, लेकिन पैसे का अपना अलग ही हिसाब है। अगर आप अपने रोजाना के खर्चों के लिए भी उधार लेते हैं, तो आप उसी आदमी की तरह आज नहीं, तो कल मुश्किल में पड़ेंगे जो हर महीने घर के भाड़े के लिए कर्ज लेता जाता है। एक दिन उसका बैंक मैनेजर 'नहीं' कह देता है और उस व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ता है।

दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी वर्ष (१९८८-८९) के केंद्रीय बजट को लें। राजस्व खर्च ५३००० करोड़ रुपए है और राजस्व प्राप्तियां ४३००० करोड़ रुपए की हैं। वित्त मंत्री अपनी आमदनी से अधिक खर्च कैसे कर सकते हैं ? उनके पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं कि वे रिजर्व बैंक से अधिक नोट छापने को कहें। इस साल राजस्व घाटा १०००० करोड़ रुपए अर्थात कर और अन्य स्रोतों से आनेवाले सरकारी राजस्व का एक चौथाई होगा। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल बात राजस्व अर्थात रोजाना के खर्चे की चल रही है। इसका एक पैसा भी विकास के लिए नहीं जाता। इस राशि का एक-एक पैसा प्रशासन के चालू खर्चों जैसे प्रतिरक्षा, पुलिस, नौकरशाही और अन्य मदों पर खर्च होता है।

दस साल पहले तक सरकार अपने राजस्व में से कुछ पैसा बचाकर ऐसी योजनाओं पर लगाती थी, जिनसे भविष्य में फायदा हो सके। अब स्थिति एकदम उलटी हो गयी है। इस साल सरकार द्वारा पूंजीगत मद से २३००० करोड़ रुपए उधार लेने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि इस पूरी रकम का इस्तेमाल पूंजीगत परियोजनाओं पर किया जायेगा। करीब २००० करोड रुपए राजस्व मद के घाटे को

पाटने में लगेंगे। नतीजतन मात्र २१००० करोड़ रुपए निवेश के लिए बचेंगे। सरकार चलाने का यह गलत तरीका है। दरअसल सरकार को अपनी राजस्व आय में से ही कुछ पैसे बचाकर विकास योजनाओं पर खर्च करना चाहिए। सभी होशियार लोग यही करते हैं। किंतु हमारी सरकार बिलकुल उलटा कर रही है। सरकार चालू आय में २५ फीसदी घाटे पर चल रही है। बाद में वह पिछले बकाये को निबटाने के लिए बाजार और रिजर्व बैंक से उधार लेगी।

हिसाब-किताब दुरुस्त नहीं: यहां पर सवाल उठता है कि आखिर सरकार अपना हिसाब-किताब दुरुस्त क्यों नहीं करती? सूद की अदायगी ही खर्च का एक बड़ा मद है। इस साल इस मद पर १४१०० करोड़ रुपए खर्च होंगे जो कुल खर्च का सबसे बड़ा भाग है। १५ साल पहले यह स्थिति नहीं थी। १९७०-७१ में कुल ३००० करोड़ रुपए के चालू खर्च में सूद की अदायगी पर मात्र ६०० करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यानी कुल खर्च का २० फीसदी। इस खर्च को सामान्य कहा जा सकता है। १९८१-८२ तक भी सूद की अदायगी पर २० फीसदी से अधिक खर्च नहीं हुआ, क्योंकि १५००० करोड़ रुपए के राजस्व खर्च में ३००० करोड़ रुपए ही सूद अदायगी पर खर्च हुए थे। इस वर्ष ५२००० करोड़ रुपए के राजस्व खर्च में सूद अदायगी की मात्रा १४००० करोड़ अर्थात करीब ३० फीसदी होगी। इससे यह पता चलता है कि पिछले लगभग एक दशक में ही सरकार ने इस तरह से कर्जे लेने शुरू किये कि उसकी आमदनी का तिहाई हिस्सा बढ़ते कर्जों के सूद की अदायगी पर लगने लगा।

यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि जब सरकार खुद कोई बचत नहीं करती, तो दिन-पर-दिन बड़ी होती जा रही योजनाओं के पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए उसे दूसरों की बचत पर निर्भर रहना पड़ता है। नतीजतन, वह खुले बाजार से उधार लेकर या भविष्य निधि या अन्य तरह की बचतों में हेरफेर करके काम चलाती है। एक स्थिति ऐसी आती है, जब इतने से भी काम नहीं चलता, तो सरकार घाटे का सहारा लेती है, जिसका अर्थ होता है मूल्यहीन कागजी मुद्रा की भरमार, जो मुद्रास्फीति को और बढ़ाती है। बिलकुल यही पिछले लगभग एक दशक में हुआ।

ऐसी स्थिति में साल दर साल कर्ज का बोझ बढ़ते जाने से अचरज नहीं होना चाहिए। आज यह कर्ज करीब २०० ००० करोड़ रुपए तक आ पहुंचा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग तिहाई भाग है। १९५०-५१ में देश पर कुल २५६५ करोड़ रुपए का कर्ज था जो सकल घरेलू उत्पादन के २५ फीसदी से थोड़ा ही अधिक था। दस साल बाद, यानी १९६०-६१ में कर्ज सकल घरेलू उत्पादन का ४६ प्रतिशत हो गया। फिर १९७०-७१ में कर्ज ५१ फीसदी हुआ और आज ६७ फीसदी तक पहुंच गया है।

अर्थशास्त्र की जानकारी न रखनेवाला व्यक्ति यहां पर पूछ सकता है कि कर्ज बढ़ा, तो उससे क्या नुकसान हुआ? फिर जनता से कर्ज का क्या वास्ता? सरकार लेती है, तो देगी भी, इसकी चिंता आम आदमी क्यों करे? तो इसका उत्तर यह है कि आम आदमी को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार या देश पर बढ़ रहे कर्ज के बोझ का असर देश के हर खास और आम पर पड़ता है। यह कर्ज महज सरकार पर न होकर देश की जनता के सिर होता है। क्योंकि सूद की देनदारियां जितनी बढ़ती जाती हैं, सरकार के पास विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए उतने ही कम पैसे बचते हैं। नतीजतन, सभी, धनी हों या गरीब, प्रभावित होते हैं, क्योंकि विकास के बिना भविष्य में कोई आमदनी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त कर्ज से मूल्य भी प्रभावित होते हैं। सरकार भारी मुद्रास्फीति के बीच ही कर्ज की अदायगी करती है। अगर सरकार आज सौ रुपए उधार लेती है और पांच साल बाद लौटाती है, तो इसका असली मूल्य तब तक आधा ही रह जाता है, क्योंकि कीमतें दूनी हो चुकी होती हैं। इस प्रकार उधार तो सौ रुपए लिये जाते हैं, लेकिन लौटाया ५० रुपए ही जाता है। सरकार के लिए यह धंधा अच्छा होगा, लेकिन जनता के लिए तो घाटे का ही है। चूंकि सभी जानते हैं कि सरकार के पास पैसा जमा कराने का मतलब उसे आधे मोल का ही कर देना है, इसलिए लोग पैसे के बारे में बहुत सोच-विचार नहीं करते और उसे यों ही खर्च करते हैं।

कंगाली के करीब: यहां पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि देश या देश की जनता कंगाली के कितने करीब पहुंच गयी हैं? इस संबंध में इतना जान लेना काफी है कि जिस साल सूद की देनदारियां उस साल के कर्ज से अधिक हो जायेंगी, सरकार दिवालिया हो जायेगी। यह हिसाब लगाना दिलचस्प तो है, लेकिन मुश्किल भी। मेरी गणना के अनुसार २००२-२००३ तक यह स्थिति आ सकती है। उस साल कर्ज की अदायगी और सूद पर १०१००० करोड रुपए खर्च होंगे—आज से सात गुना— और उस वर्ष ९९००० करोड़ रुपए ही उधार लिए जा सकेंगे। तब तक देश पर कुल कर्ज ११००००० करोड़ रुपए हो चुका होगा, यानी उस साल के सकल घरेलू उत्पादन से भी अधिक। नतीजतन देश को अपनी सकल राष्ट्रीय आय अपने कर्जदारों के यहां बंधक रख देनी होगी। यहां पर यह बता देना जरूरी है कि देश में सिर्फ सरकार ही दिवालिया संस्था नहीं है। दूसरीं सरकारी संस्थाओं की भी यही हालत है। सरकारी हिसाब-किताब का आकलन करते समय इसका भी पता लगता है। सरकारी उपक्रमों को ही लें। इनकी संख्या २०० से ऊपर है। और इनमें से कुछेक ही फायदे में रहते हैं। १९८६-८७ में इन सभी ने १४० करोड़ रुपए का घाटा दिया। वह तो कहिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तया इंडियन आयल ने १९१२ करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, वरना यह घाटा और अधिक हो जाता। चूंकि ये एकाधिकार कंपनियां हैं, इसलिए इनकी लागत और मूल्य में कोई संबंध नहीं होता। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपने कच्चे तेल की कीमत दुनिया के स्तर पर ही रखे हुए है, जबकि इसे निकालने में काफी कम खर्च आता होगा। इंडियन आयल अपने ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूलता है और भारत में जिस कीमत पर पेट्रोल मिलता है, वह शायद दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन इन कंपनियों के मुनाफे के अलावा अन्य सरकारी उपक्रमों से शायद ही कुछ अतिरिक्त पैसा आता हो। सरकार ने इन उपक्रमों से पिछले साल मात्र ५०० करोड़ रुपए का लाभांश प्राप्त किया और इस साल भी उसे इतनी ही रकम मिलने की उम्मीद है। वह भी तब जब ये उपक्रम अपने सामान की ऊंची कीमत लेते हैं। पिछले महीने कोयले और कुछ किस्म के इस्पात की कीमत बढ़ायी गयी। उल्लेखनीय है कि भारतीय इस्पात दुनिया में सबसे मंहगा है और यही स्थिति अन्य चीजों की भी है।

सरकारी उपक्रमों से नुकसान: सरकार जो कर्ज लेती है, उसका अधिकांश भाग इन्हीं इकाइयों को, चाहे वे केंद्र की हों या राज्य की, जाता है। राज्य सरकारों के पास बिजलीघर और परिवहन निगम तो हैं, किंतु ये सभी घाटा ही देते हैं। ऊर्जा मंत्री वसंत साठे के अनुसार सरकारी विद्युत उपक्रमों का घाटा १३००० करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह रकम छोटी नहीं, इतनी रकम से आठवीं योजना में प्रस्तावित एक तिहाई निवेश संभव हो सकता है। यही स्थिति परिवहन उपक्रमों की है। सिर्फ दिल्ली में ही अभी तक ४५० करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, जिसमें दिल्ली परिवहन निगम का ही घाटा प्रति

वर्ष १०० करोड़ रुपए रहता है। उत्तर प्रदेश, जो शायद इस दृष्टि से सर्वाधिक अकुशल राज्य है, में परिवहन निगम का घाटा तो १००० करोड़ रुपए की सीमा लांघ चुका है।

बिजलीघरों और परिवहन इकाइयों को छोड़कर सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमों में मार्च १९८८ तक कुल ६३००० करोड़ रुपए लगाये गये थे। अगर इन दोनों को भी इसमें जोड़ लिया जाये, तो कुल निवेश १५०००० करोड़ रुपए तक पहुंच जायेगा, यानी संपूर्ण राष्ट्रीय कर्ज के बराबर। अब यह जानना जरूरी है कि देश को इतने भारी निवेश से हासिल क्या होता है? लाभांश के रूप में ५०० करोड़ रुपए और कुछ इकाइयों से ५०० करोड़ तक का मुनाफा। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किये गये इतने हजार करोड़ रुपए में सिर्फ १.० हजार करोड़ रुपए का फायदा! यदि इतनी बड़ी रकम लगाने पर १० फीसदी अर्थात १५००० करोड़ रुपए का फायदा भी होता, तो सरकार को कर्ज लेने, बजट में घाटा दिखाने अथवा रिजर्व बैंक से नोट छपवाकर काम चलाने की जरूरत नहीं पडती।

> जिस साल सूद की देनदारियां उस साल के कर्ज से अधिक हो जायेंगी, सरकार दिवालिया हो जायेगी। एक गणना के अनुसार २००२-२००३ तक यह स्थिति आ सकती है। उस साल कर्ज की अदायगी और सूद पर १०१००० करोड़ रुपए खर्च होंगे—और उस वर्ष ९९००० करोड़ रुपए ही उधार लिए जा सकेंगे। तब तक देश पर कुल कर्ज ११००००० करोड़ रुपए हो चुका होगा, यानी उस साल के सकल घरेलू उत्पादन से भी अधिक।

विदेशी कर्ज: अब आइये विदेशों से लिये जानेवाले कर्जों पर भी नयी तरह से ध्यान दें। यह कर्ज ५५००० करोड़ रुपए अर्थात देश के आंतरिक कर्ज के आधे के बराबर हो गया है। यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर इतना कर्ज लिया क्यों गया? सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत जितनी चीजों का आयात करता है, उसके बराबर मूल्य का अपना सामान बाहर बेच पाने में वह सफल नहीं रहा है। विदेश व्यापार के इस फासले को भरने के लिए उसे कर्ज की जरूरत होती है। सवाल यह है कि निर्यात में इतनी मुश्किल क्यों है? यहां भी वही कारण कारगर हैं जिनके चलते सार्वजनिक क्षेत्र इतना घाटा दे रहा है। भारतीय सामान की कीमत काफी अधिक है, क्योंकि भारत में सामानों पर लागत ज्यादा आती है। लागत ज्यादा होने का कारण सिर्फ अकुशलता है।

मिसाल के तौर पर इस्पात को ही लें। उल्लेखनीय है कि भारत कभी दुनिया में सबसे सस्ता इस्पात बनाता था। आज भारत नहीं दक्षिण कोरिया सबसे सस्ता इस्पात बनाता है जबकि उसके पास न लौह अयस्क है, न कोयला। यही स्थिति जापान की भी है। वह भी एक समय सबसे सस्ता इस्पात बनाता था। दक्षिण कोरिया भारत से लौह अयस्क, ब्राजील और आस्ट्रेलिया से कोयला मंगाता है और भारत की तुलना में एक तिहाई कम कीमत पर इस्पात तैयार करता है। दक्षिण कोरिया में भी सार्वजनिक क्षेत्र है—जापान में नहीं है—लेकिन वह भारत की तरह काम नहीं करता। वहां के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने पोहांग स्टील प्लांट नाम की इकाई के साथ २० साल पहले काम शुरू किया था। तब उस इकाई की क्षमता १ करोड़ टन थी और आज इस इकाई में प्रति वर्ष दस करोड़ टन स्टील का उत्पादन होता है जो भारत की सबसे बड़ी इकाई से तीन गुना है। इसका विस्तार अभी भी चल रहा है। भारत की टाटा स्टील कंपनी करीब ८० साल पुरानी है, पोहांग से चौगुनी और यहां पोहांग का एक चौथाई उत्पादन ही होता है। इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय निवेश की यह दुर्गति क्यों है।

सार्वजनिक क्षेत्र में क्रांति: सरकार द्वारा लिये गये कर्जों का अधिकांश हिस्सा चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र को जाता है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज में क्रांतिकारी सुधार लाये बिना वित्तीय स्थिति में सुधार संभव नहीं है। सचाई तो यह है कि अब समय आ गया है कि इन सफेद हाथियों के बारे में कोई फैसला किया जाये जो १०-२० साल पहले तक उपयोगी हो सकते थे, लेकिन अब उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। यह बात सिर्फ भारत पर ही नहीं, सभी देशों पर लागू होती है। इनमें ब्रिटेन और सोवियत संघ भी शामिल हैं। लेबर पार्टी की सरकार ने ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया था। सोवियत संघ में तो सार्वजनिक क्षेत्र ही है और इसका कामकाज सुधारने के अभियान के तहत मिखाइल गोर्बाचेव ने करीब १० लाख मजदूरों और प्रबंधकों की छुट्टी कर दी है और अभी बहुतेरे लोगों की छंटनी होनी है। वे इस अभियान को पेरेस्त्रोइका कहते हैं। भारत में भी पेरेस्त्रोइका की जरूरत है। इसकी शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र से होनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की एक ही कमजोर इकाई सरकारी वित्त को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए काफी है।

किंतु सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? इस संबंध में किसी कमजोर सरकार से पहल की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र किसी न किसी तरह से जन कल्याण से जुड़े हैं। यदि उन्हें छुआ गया, तो वामपंथियों की ओर से शोर मचेगा। ब्रिटेन में स्थिति दूसरी थी। मारग्रेट थैचर में इतना दम था कि उन्होंने वामपंथियों की आवाज पर ध्यान न देकर अर्थव्यवस्था में मनमाफिक बदलाव किया। किंतु भारत में तो सार्वजनिक क्षेत्र पवित्र गाय बन गया है, जिसे राजीव गांधी भी, जो इसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, छू नहीं सकते। यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि राष्ट्रीय बजट, पारिवारिक बजटों का सकल योग है। अगर राष्ट्रीय बजट में घाटा रहता है, तो संभावना बनती है कि अन्य सभी बजटों में भी घाटा रहेगा। घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि घाटे को कागजी मुद्रा छापकर भरा जाता है और इससे कीमतें बढ़ती हैं। महंगाई के कारण लोग अपना खर्च चलाने के लिए अपनी बचत का भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आज पूरे देश में यही तो हो रहा है।

घरेलू बचत दर, जिससे बचत का मुख्य पैसा आता है, १९५७ में सकल घरेलू उत्पादन का करीब ८ फीसदी थी। यह बढ़कर अगले दस वर्षों में १२ फीसदी हो गयी और उसके बाद १९७८-७९ में १८ फीसदी तक पहुंच गयी। उल्लेखनीय है कि ७८-७९ ही आखिरी वर्ष था, जब राजस्व आय में भी कुछ अधिशेष रह गया था। इसके बाद तो बचत दर निरंतर घटती गयी और ८४-८५ में १८ प्रतिशत से घटकर १५ प्रतिशत हो गयी। संप्रति यह कुछ बेहतर तो है, किंतु आज भी अधिकतम से नीचे ही है। यही स्थिति उन कंपनियों की भी है जो बचत के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। १९७९-८० में इनके यहां बचत की दर (सकल घरेलू उत्पादन का) २.२ फीसदी थी, जो अब घटकर १.७ फीसदी है।

अमरीका से मिलती-जुलती स्थिति: आर्थिक स्थिति का इतनी गहरायी से अध्ययन करने के पश्चात यह बात उजागर होती है कि कई अर्थों में भारत की हालत अमरीका की तरह है। अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के शासनकाल में १९८१ में पहली बार अमरीका में घाटे का बजट पेश किया गया और उसके बाद स्थिति सुधरी ही नहीं। उनका बजट घाटा उनके सकल घरेलू उत्पादन का ३.५ फीसदी है। भारत की भी कमोबेश यही स्थिति है। उनका चालू मद का घाटा—व्यापार घाटा और अप्रत्यक्ष आय—भी सकल घरेलू उत्पादन का ३.५ फीसदी है। भारत की स्थिति भी लगभग समान है। उनका डालर अन्य मुद्राओं, खासकर जापानी येन, की तुलना में गिरता जा रहा है और आज अपने पुराने मूल्य के आधे पर रह गया है। इसी तरह भारत के रुपए का मूल्य भी पहले के मूल्य का आधा ही रह गया है। यदि यह कहा जाये कि दोनों देश एक ही नाव पर सवार हैं, तो किसी हद तक सही होगा। किंतु एक बड़ा फर्क तो है ही। अमरीका दुनिया का सबसे अमीर देश है जिसका सकल घरेलू उत्पादन ४ खरब डालर का है। जबकि भारत सबसे

गरीब देशों में से एक है, जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ४००० रुपए अर्थात ३०० डालर से भी कम है। इतना पैसा तो अमरीका का कुशल मजदूर १० घंटे के काम में ही कमा लेता है। यह सही है कि अमरीका पर भी काफी कर्ज है, उसके सकल घरेलू उत्पादन के एक तिहाई के बराबर, लेकिन वह उसे संभाल सकता है। लेकिन हमारा कर्ज उसके अनुपात से अधिक है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पादन के दो तिहाई तक पहुंच गया है। नतीजतन भारत अमरीका से भी तेज रफ्तार से कर्ज के दलदल में फंस गया है जिससे उबरना लोहे के चने चबाना है।

अमरीका के नये राष्ट्रपति जार्ज बुश ने अमरीका की बागडोर संभालते ही कहा है कि कर्ज से निबटना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जाहिर है अमरीकी कानून के अनुसार उन्हें किसी भी कीमत पर इसे १९९० के पहले कम करना होगा। किंतु अफसोस इस बात का है कि भारत में न कोई कानून है और न राजनेता इस कर्ज का जिक्र करते हैं। इसी महीने केंद्रीय वित्त मंत्री चह्वाण अपना पहला और शायद आखिरी बजट पेश करेंगे और संभावना यही है कि वे कर्ज की चर्चा भी नहीं करेंगे। बजट दस्तावेजों में कर्जे का जिक्र एक छोटे पैराग्राफ में किया जाता है और इसमें भी जो आंकड़े दिये जाते हैं, वे भ्रामक होते हैं। कुछ महीने पहले तक सरकार यही कहती रही है कि विदेशी कर्ज २५००० करोड रुपए से अधिक नहीं है। जोर डालने पर एडुआर्डो फेलेरियो ने स्वीकार किया है कि यह कर्ज ५०००० करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इससे पता चलता है कि सरकार खुद को मुश्किल में डालने वाली बातों पर किस गैर जिम्मेदार तरीके से काम करती है। ऐसी संभावना है कि इस साल विदेशी कर्ज ७५००० करोड रुपए से अधिक हो जायेगा और कुछ वर्षों में ही यह १००००० करोड़ रुपए की सीमा को पार कर जायेगा।

> **भारत में भी पेरेस्त्रोइका की जरूरत है। इसकी शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र से होनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की एक ही कमजोर इकाई सरकारी वित्त को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए काफी है।**

मजबूरी : अब सवाल यह है कि करीब-करीब दिवालिया हो गयी सरकार इस स्थिति का मुकाबला कैसे कर सकती है? अगले साल का बजट जो शीघ्र पेश किया जाने वाला है, पिछले वर्ष से कोई अलग नहीं होगा, सिर्फ आंकड़े बदल जायेंगे, बजट घाटा थोड़ा बढ़ जायेगा, रुपए का मोल कुछ और घट जायेगा और विकास दर में कुछ सुधार होगा।

रूसी लोग भी हमारी ही तरह हरदम यह कहते थे कि उनकी अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या उन्हें सस्ता मकान और ब्रेड नहीं मिलता था? क्या ख्रुश्चैव यह नहीं कहते थे कि वे सारे पूंजीपतियों को दफना देंगे? इस बीच रूसी बजट का घाटा और कर्ज बढता गया। अब जाकर गोर्बाचिव ने स्वीकार किया है कि रूबल का वह मूल्य नहीं रह गया है जो पहले था। अधिकृत रूप से इसे डालर से महंगा बताया जाता है, किंतु असलियत यह है कि अब रूबल २५-३० सैंट से अधिक कीमत का नहीं रह गया है। इस आधार पर रूस के सकल राष्ट्रीय उत्पादन को यूनान से अधिक नहीं माना जा सकता है जो बहुत ही गरीब और छोटा देश है। भारत भी उसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह कर्ज का गुब्बारा किसी भी दिन फूट सकता है।

—डा० जय दुबाशी

चुटकी पान मसाला प्यार के रिश्तों में एक अनोखी ताज़गी और मीठी-मीठी महक लाता है। हर मौके, हर महफ़िल में रंग जमाता है। सौंफ़, छुआरा और इलायची वाला चुटकी पान मसाला कितना है निराला!
चुटकी की चुटकियां
ज़िन्दगी की भोली-भाली मस्तियां
अब नये सजधज के साथ नये आकर्षक पॉउच पैक में!
Chutki
प्यार का मस्ती भरा एहसास
चुटकी पान मसाला!

बजट पूर्वानुमान

राहत की सांसत

पहले की तरह इस बार फिर आर्थिक विश्लेषण की शुरुआत इसी वाक्य से करना उचित होगा कि अगला बजट (८९-९०) आम आदमी के लिए ज्यादा फायदे का नहीं होगा। इस संबंध में यह भी कहना अनुचित न होगा कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव पूर्व पेश किया जानेवाला बजट नर्म न होगा। बल्कि उम्मीद तो कुछ ऐसी ही है कि हर साल की तरह अगला चुनाव-पूर्व बजट भी कमरतोड़ होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार चुनाव खुद हारना चाहती है या उसे आम आदमी से कोई वास्ता नहीं। सचाई तो यह है कि आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड हो गयी है कि चाहते हुए भी सरकार असमर्थ है। यानी नर्म बजट न पेश कर पाना उसकी एक मजबूरी हो गयी है।

उपर्युक्त आकलन की सचाई जानने के लिए मामूली-सी गणनाओं पर ध्यान देना ही काफी है। ८८-८९ के बजट के अनुसार सरकार को कम से कम ८०,००० करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं तथा करों के रूप में मात्र ३५,००० करोड़ रुपए की ही उगाही हो सकी है। अन्य स्रोतों से अधिकतम आय ४,००० करोड़ रुपए भी मान ली जाये तब भी खर्च और आय के बीच ४१,००० करोड़ रुपए का फासला बरकरार है।

अब सवाल यह है कि ४१,००० करोड़ रुपए का फासला छोटा तो है नहीं। इसकी भरपायी करने के लिए सरकार सिवाय कर्ज लेने या मूल्यहीन मुद्रा की भरमार करने के और क्या कर सकती है? ऐसा तो है नहीं कि इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जरूरी खर्चों में कटौती करेगी। स्थिति यह है कि रक्षा मंत्रालय ने पहले से ही अतिरिक्त ४००० करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेज दिया है। यदि यह मान लिया जाये कि अतिरिक्त ४००० करोड़ का आवंटन नहीं किया जायेगा, तो खुश रखने के लिए १,००० रुपए अतिरिक्त तो देने ही पड़ेंगे। साथ ही घाटा चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, सुरक्षाकर्मियों को दिये जानेवाले वेतन या पेंशन में तो कटौती की नहीं जा सकती। इसलिए यदि वर्तमान दर को ही मद्देनजर रखा जाये, तो भी इस अकेले मद पर सरकार को ५०० करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इसी के साथ न्यूनतम मुद्रास्फीति भी कम से कम १३०० करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ तो लादेगी ही। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि सुरक्षा मद पर १४,००० करोड़ रुपए के खर्च का सीधा मतलब है कि अगले वर्ष नये सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अतिरिक्त इस मद पर खर्च घटाने का कोई और रास्ता नहीं होगा।

सबसे बड़ी मुश्किल : सरकार की दूसरी बड़ी मुसीबत सूद की अदायगी है। जाहिर है, जिस वायदे पर जहां से कर्ज लिया गया है, यदि मूल के साथ ब्याज भी रोका जाता है, तो स्थिति बिगड़ सकती है। स्थिति यह है कि सरकार पर कुल आंतरिक कर्ज बढ़ते-बढ़ते लगभग १०,७००० करोड़ तक पहुंच गया है, यानी केवल सूद के रूप में ही ९,००० करोड़ रुपए सालाना खर्च करने की मजबूरी।

हां, इतना जरूर है कि रियायतों में कमी करके सरकार खर्चों में कटौती कर सकती है। किंतु क्या सरकार रियायतें घटाकर अस्तित्व में रह सकती है? सचाई तो यह है कि भले सरकार को और घाटा उठाना पड़े, किंतु रियायतों में कटौती करना उसके अस्तित्व के लिए खतरनाक है। स्थिति यह है कि सिर्फ खाद्यान्नों पर ही दी जानेवाली रियायतें कुल रियायतों की आधी होती हैं। यानी ३,००० करोड़ रुपए से ज्यादा। फिर उत्पादन और इस्तेमाल के बढ़ते जाने के साथ इस आंकड़े में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। ऐसा अनुमान है कि अनाज की पैदावार में २५ करोड़ टन की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ी हुई पैदावार में से भी सरकार को कम से कम ३० लाख टन की खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी। यानी किसानों पर अतिरिक्त ६,००० करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा और इतनी रकम पर न्यूनतम ५०० करोड़ रुपए रियायत के रूप में जायेंगे।

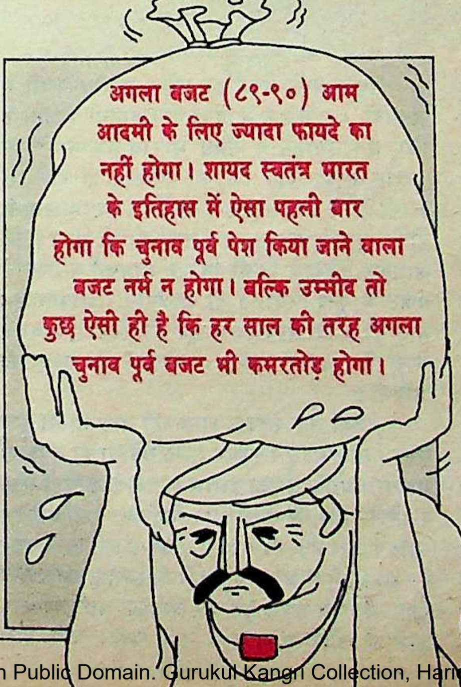
अगला बजट (८९-९०) आम आदमी के लिए ज्यादा फायदे का नहीं होगा। शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि चुनाव पूर्व पेश किया जाने वाला बजट नर्म न होगा। बल्कि उम्मीद तो कुछ ऐसी ही है कि हर साल की तरह अगला चुनाव पूर्व बजट भी कमरतोड़ होगा।

असंतोष कम नहीं : यहां पर इस बात का उल्लेख करना अत्यंत जरूरी है कि सरकार रियायतों के रूप में इतना कुछ खर्च कर रही है तब भी स्थिति यह है कि देश का किसान सरकार से संतुष्ट नहीं है। पिछले साल किसानों के असंतोष को मद्देनजर रखते हुए केंद्र ने कृषि के मद में रियायतों को छोड़कर ६०० करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किये थे। फिर भी असंतोष घटा नहीं। ऐसी स्थिति में कृषि के मद में कटौती करके खर्च घटाना या रियायतों पर लगाम लगाना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। नतीजतन कुल रियायतें न्यूनतम १,००० करोड़ रुपए तक जायेंगी। यानी सिर्फ रियायतों पर ही ९,००० करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

इस तरह से उपर्युक्त चारों मदों पर ही न्यूनतम कुल ३२,००० करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन चारों मदों पर होनेवाले खर्च को अलग कर देने पर शिक्षा, चिकित्सा-सेवा, समाज कल्याण और प्रशासन पर होनेवाला रोजमर्रे का खर्च बाकी रह जाता है। इन मदों पर सरकार दो तरह से खर्च करती है। कुछ तो वस्तुओं की खरीद और सेवाएं लेने पर तथा कुछ कर्मचारियों के वेतन पर। यदि मुद्रास्फीति की न्यूनतम दर को ही सामने रखा जाये, तो भी वस्तुओं की खरीद और सेवाओं पर होनेवाले खर्च में १० प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, बशर्ते सरकार उतनी ही वस्तुएं खरीदे तथा सेवाएं ले, जितनी उसने पिछले साल ली थीं। इसी तरह वेतन पर होनेवाले खर्च में भी ९-१० प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। यानी यदि नये रोजगार उपलब्ध न कराये जायें, तो भी खर्च २२,०००-२५,००० करोड़ रुपए के बीच होगा।

नये खर्चे : इनके अतिरिक्त कुछ नये मद भी हैं जिन पर खर्च जरूरी है तथा उन पर खर्च करने से सरकारी तिजोरी और प्रभावित होगी। गत नवंबर में सत्तारूढ़ दल ने प्रत्येक गरीब महिला को दो साड़ियां, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करनेवाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार, प्राथमिक विद्यालयों के गरीब बच्चों को दिन का आहार सुलभ कराने तथा कुछ अन्य योजनाएं बनायी हैं। एक साल तो बहुत बड़ी बात है, इन योजनाओं पर तो तीन साल में भी अमल कर पाना संभव नहीं नजर आता, क्योंकि इन योजनाओं पर होनेवाले कुल खर्च का चौथाई हिस्सा भी हर वर्ष उगाहना आसान बात नहीं है। उसके बाद भी वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह पता करे कि उक्त योजनाओं पर अधिकतम कितना खर्च करने की गुंजाइश बन सकती है। इसलिए ऐसी उम्मीद है

कि सरकार येन-केन-प्रकारेण इन योजनाओं के लिए ३०००-४००० करोड़ रुपए के बीच आवंटित करेगी।

उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार यदि सरकार खर्चे आवंटित करती है, तो उपर्युक्त सभी मदों के खर्चों को जोड़ने पर कुल राशि ६०,००० से ७६,००० करोड़ रुपए के बीच आयेगी। योजनाबद्ध खर्चे, जिनका बहुत बड़ा भाग करों, कर्जों और घाटों के रूप में सामने आता है वह भी किसी भी कीमत पर २०,००० करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। यानी सरकार को कुल ८०,०००-८७,००० करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी।

अब सवाल यह है कि आखिर इतने रुपए आयेंगे कहां से ? यदि कर राजस्व को बढ़ाया जाता है, तो उसका सीधा असर सीमा तथा उत्पाद शुल्क पर. पड़ेगा। जहां तक प्रत्यक्ष करों—आयकर आदि—की बात है, उनका बढ़ाया जाना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष करों के रूप में कुल कर राजस्व का एक तिहाई भाग ही आता है। इसलिए यदि इन करों में २० प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाती है, तो २,००० करोड़ रुपए से अधिक मिलने की संभावना नहीं है। फिर इस बात का भी तो खयाल रखना है कि उद्योगपति और व्यापारी पहले से ही करों में रियायत की आवाज बुलंद कर रहे हैं और राजीव गांधी ने कई बार दोहराया भी है कि प्रोत्साहन के रूप में निजी क्षेत्र को करों में रियायत देना उनकी नीति है। ऐसी स्थिति में किसी तरह का बोझ डालना धनवानों को नाराज करना ही तो होगा। यही नहीं, चुनाव-पूर्व पेश होनेवाले बजट में सरकार इस बात पर खास ध्यान देती है कि उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी न करके कुछ रियायत दी जाये, क्योंकि सरकार यह नही चाहती की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ें। किंतु सरकार के सामने इस वर्ष इतना बड़ा आर्थिक संकट है कि चुनाव-पूर्व का बजट होने के बावजूद वह असमर्थ नजर आ रही है।

कंगाली की बाबत : अब तो बस एक रास्ता है कि सरकार के सामने जो विकल्प हैं उन्हीं में से किसी एक पर अमल करे, क्योंकि पूरी तरह से चुनावी बजट तैयार करना कंगाली की ओर बढ़ती आर्थिक प्रक्रिया को त्वरित करेगा। इसलिए सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जिस रास्ते को अपनाने से नुकसान कम पहुंचे और अस्तित्व बरकरार रहे उसे ही अपनाया जाये। सरकार के समक्ष एक रास्ता तो यह है कि चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए सरकार पुन: वित्तीय घाटे और कर्ज का सहारा ले। दूसरा विकल्प यह है कि सरकार अपने खर्चों जैसे रियायतें, रोजगार सुलभ कराने, शिक्षा, चिकित्सा-सेवा या समाज कल्याण, में कटौती करे। तीसरा विकल्प यह है कि सरकार कुछ ऐसा समीकरण तैयार करे जिससे सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे। यानी एक ऐसा बजट पेश किया जाये जो निराश करने के साथ-साथ आशान्वित भी करे, ताकि कुरसी बची रहे।

जादुई बजट : जाहिर है, तीसरा विकल्प ही समझ में आनेवाला है। किंतु सवाल यह है कि सरकार ऐसा जादुई बजट तैयार करने के लिए करेगी क्या ? क्योंकि सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है कि कर राजस्व में कुछ बढ़ोतरी की जाये तथा वित्तीय घाटे और कर्ज का सहारा लिया जाये। हां, इतना जरूर हो सकता है कि उधार देनेवाले स्रोतों से ज्यादा उधार न लिये जायें। साथ ही, सरकारी दफ्तरों पर होनेवाले खर्चों तथा सरकारी विभागों के रोजमर्रे के खर्चों में कटौती की जा सकती है। किंतु ग्रामीण रोजगार पर खर्च बढ़ाने होंगे तथा गरीबों को फुसलानेवाले कुछ अन्य कार्यक्रमों पर कुछ खर्च करना होगा। साथ ही, गरीबों की जरूरत की चीजों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की जायेगी। अनाज, गुड़ तथा तेल की कीमतें नियंत्रित रखने का प्रयास होगा तथा मोटे कपड़ों को भी वाजिब दाम पर बिकवाया जायेगा।

> **आगामी बजट**
> **कैसा होगा उसका दारोमदार**
> **राजीव गांधी द्वारा**
> **विकल्प चुनने की क्षमता पर**
> **निर्भर करेगा। यदि**
> **उन्हें कंगाली का डर न होगा,**
> **तो बजट अवश्य नर्म होगा**
> **अन्यथा बजट से विशेष रियायत**
> **की उम्मीद नहीं।**

कुछ इसी तरह का संकेत राजीव गांधी ने ज़नवरी '८९ के शुरू में दिया था। आठवीं योजना के लिए धन उगाहने के संबंध में राय पेश करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर राजस्व में बढ़ोतरी करनी होगी तथा सरकारी खर्चों पर लगाम लगानी होगी। दूसरी ओर कुछ इस तरह की भी खबर है कि आयकर देनेवाले किसी विशेष आयवर्ग को अगले बजट में कुछ रियायत दी जायेगी। संभावना इस बात की है कि आयकर से छूट की सीमा १८,००० रुपए से बढ़ाकर २२,०००-२५,००० रुपए की जायेगी।

जहां तक उत्पाद शुल्क की बात है, तो कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जिनपर शुल्क बढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनका इस्तेमाल देश के करोड़ों लोग करते हैं। मिसाल के तौर पर मिट्टी का तेल, माचिस आदि। जहां तक बीड़ी तथा बीड़ी के पत्ते का सवाल है, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी से विशेष हानि नहीं होगी, क्योंकि इससे पूर्व भी सिगरेट आदि के दाम बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यही हाल धोनेवाले साबुनों तथा पाउडरों का भी है। चूंकि गरीब जनता महीने में एक या दो अदद साबुन ही खरीदती है, इसलिए उनके दामों में बढ़ोतरी से खास नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए बीड़ी, बीड़ी के पत्ते, शराब, धोने के साबुन, पाउडर आदि जैसी वस्तुओं से सरकार की आमदनी कुछ बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा सभी वस्तुओं पर निडर होकर कर बढ़ाये जा सकते हैं, क्योंकि उससे देश की गरीब आबादी प्रभावित नहीं होगी।

ग्रामीणों पर नजर : यहां पर इस बात का खयाल रखना बहुत जरूरी है कि देश की ग्रामीण आबादी की आय का प्रमुख साधन कृषि ही है। यदि ग्रामीण आबादी के असंतोष को घटाना लक्ष्य होगा, तो सरकार को कुछ अतिरिक्त रियायतों की घोषणा करनी होगी, क्योंकि इस आबादी का दो तिहाई भाग आम महंगाई से इतना प्रभावित नहीं होता जितना अनाज के दाम बढ़ने से उस पर बोझ बढ़ता है। इसलिए यदि कोई ऐसा रास्ता निकल आता है जिससे अनाज की कीमतें नियंत्रण में रहें और ग्रामीण आबादी की आय सुरक्षित रहे, तो संभव है सरकार को ग्रामीण आबादी का सहयोग मिल जाये। साथ ही, ग्रामीण परिवारों की संख्या का लगभग आधा भाग अतिरिक्त आय के लिए परेशान रहता है। इसलिए सरकार यदि रोजगार कार्यक्रमों पर थोड़ा भी ज्यादा खर्च करने की ठान लेगी, तो आधी ग्रामीण आबादी को पहले से बेहतर होने का अहसास हो जायेगा।

बहरहाल, यदि राजीव गांधी भी इसी अंदाज में सोच रहे हैं, तो यह निश्चित है कि अगले बजट (१९८९-९०) में अनेक उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद तथा सीमा शुल्क बढ़ेंगे। उपभोक्ता वस्तुओं में से उन वस्तुओं पर तो विशेष बढ़ोतरी होगी जिन्हें 'जरूरत' में शामिल नहीं किया जाता। हां, इस बात की गुंजाइश जरूर है कि ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी पर शुल्क न बढ़े। यात्री कारें, आधुनिक किचेन के सामान, शीशे के सामान तथा कीमती कपड़ों पर भी हो सकता है शुल्क न बढ़े। नतीजतन वित्तीय घाटा और कर्ज बढ़ेगा, किंतु संख्या १९८७-८८ जैसी नहीं होगी जब वित्तीय घाटा लगभग १०,००० करोड़ रुपए था। रही कर्ज की गणना, तो यह इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने कर राजस्व या कितने वित्तीय घाटे की योजना तैयार की गयी है।

वैसे जहां तक राजीव गांधी की बात है, तमिलनाडु के चुनाव से उन्हें यह सबक मिल गया है कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा जरूरी राजनीति है। इसलिए वे अपने संगठन को मजबूत करने तथा उसकी सक्रियता पर ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त किये जा सकें। आगामी बजट कैसा होगा, इसका दारोमदार राजीव गांधी द्वारा विकल्प चुनने की क्षमता पर निर्भर करेगा। यदि उन्हें कंगाली का डर न होगा, तो बजट अवश्य नर्म होगा अन्यथा बजट से विशेष रियायत की उम्मीद नहीं।

—कुमारेश चक्रवर्ती

कलियुगी अग्नि परीक्षा

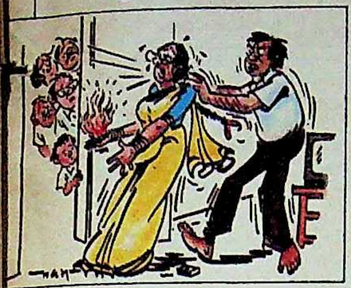

हमारे समाज में ऐसे पुरुष मिल जायेंगे, जो खुद भौंरे की तरह अनेक स्त्रियों पर मंडराते रहते हैं। उन्हें तब तो स्वयं को राम और सत्यवान के आदर्शों पर चलने की सुध नहीं रहती, लेकिन यदि उनकी बीवियां किसी से बात भी कर लें, तो वे अपने सिर पर आसमान उठा लेते हैं और बेचारी पत्नी की लानत-मलामत कर डालते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्गा निवासी एक खब्ती पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही कुछ सलूक कर अपनी बेवकूफी की मिसाल कायम की है। 'रामायण' में सीता की अग्नि परीक्षा से प्रेरित होकर एक पढ़े-लिखे, पेशे से दर्जी पति ने अपनी पत्नी की पवित्रता की परीक्षा लेने की सोची और उसने अपनी पत्नी की हथेली पर कपूर रखकर दियासलाई लगा दी। बेचारी पत्नी मजबूर थी। उसका हाथ जलता रहा और पीड़ा से कराहती रही, लेकिन क्या करती, पत्नी जो ठहरी। जब उसकी हथेली जल गयी, तो उसने सोच लिया कि उसकी पत्नी पवित्र होती, तो जैसे सीताजी अग्नि से बाहर साबुत निकल गयी थीं, वैसे ही उसकी पत्नी की हथेली भी नहीं जलती। उसको यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का चरित्र संदिग्ध है और उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल तो वह बेचारी तुमकुर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दी गयी है।

और वे डाकू बनने चले

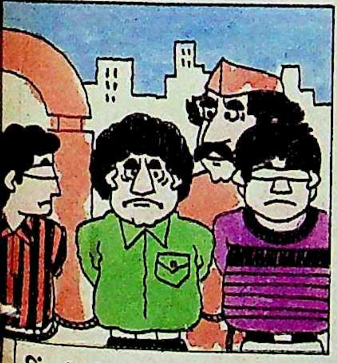

हिंदी फिल्मों और दूरदर्शन पर प्रसारित होनेवाले सीरियलों का हमारे ऊपर अच्छा असर पड़े या न पड़े, लेकिन बुरा असर पड़े बिना नहीं रह पाता। हमारी नयी पीढ़ी, उसमें भी खासकर स्कूली बच्चों पर, मारधाड़ और हिंसावाली फिल्मों का कितना बुरा असर पड़ा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोरखपुर में उस समय मिला, जब हाईस्कूल के तीन विद्यार्थियों ने अपने ही एक साथी के अपहरण का नाटक कर पचास हजार रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। गोरखपुर के जुबिली इंटर कालेज के हाईस्कूल के तीन छात्रों—राजेश, संदीप और रामकिशोर ने अपने ही सहपाठी सूरज को अपने कब्जे में कर उसके पिता डा० सुशील कुमार श्रीवास्तव के गोलैघर स्थित क्लीनिक पर डकैतों वाली स्टाइल में एक पत्र लिखकर फेंक दिया कि यदि साढ़े तीन बजे तक बुढ़िया माई के स्थान पर पचास हजार रुपए नहीं पहुंचे, तो उनके पुत्र को खतम कर दिया जायेगा। पत्र फेंकने के बाद तीनों सूरज की साइकिल लेकर कुसुमी जंगल चले गये। जब डा० सुशील ने अपनी क्लीनिक में मिला पर्चा पढ़ा, तो उनके होश फाख्ता हो गये। वे दौड़े-दौड़े राजघाट थाने पहुंचे। राजघाट पुलिस पर्चे के अनुसार कुसुमी जंगल में बुढ़िया माई के स्थान पर एक बैग लेकर पहुंच गयी। वहां अचानक रामकिशोर दिखायी दिया, जिसे पुलिस ने धर-दबोचा। रामकिशोर के पकड़े जाने पर संदीप भी पकड़ लिया गया और अपहरण का सारा परदाफाश हो गया। रामकिशोर और संदीप से पूछे जाने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया कि वे सूरज के पिता से पैसा इसलिए ऐंठना चाहते थे, ताकि मौज कर सकें।

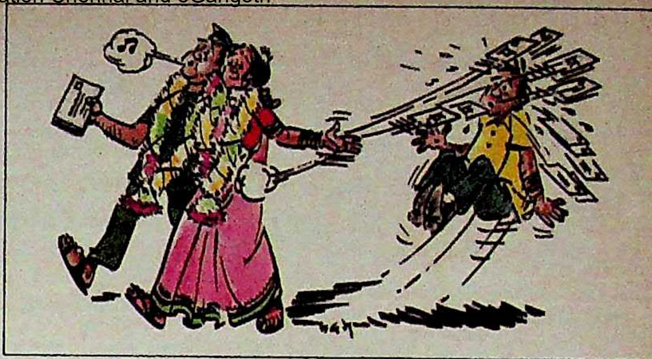

डाकिये का कमाल !

पढ़ने-लिखने का कोई फायदा होता हो या न होता हो, लेकिन न पढ़े-लिखे होने से नुकसान बड़ा-से-बड़ा हो सकता है। इसका खमियाजा एक पतिदेव को उस समय उठाना पड़ा, जब वे परदेश से लौटकर आये। उनको पता चला कि उनकी पत्नी तो डाकिये की हो चुकी है। किस्सा बिजनौर के धामपुर का है। अपनी बीवी को पतिदेव महोदय परदेस से जो प्रेमपत्र भेजते थे, वह बेचारी ठहरी अनपढ़, सो पढ़ तो पाती नहीं थी, इसलिए वह डाकिये से पढ़वा लिया करती। लेकिन डाकिया कुछ ऐसा दिलफेंक और इश्कमिजाज निकला कि वह कुछ इस लहजे में सांसें-उसांसें भरकर पढ़ता कि उस परदेसी की पत्नी सुध खो बैठती और अपने पति की याद में डूबने के बजाय डाकिये की यादों में खोती चली गयी। वह कब डाकिये की हो गयी, उसे खुद पता नहीं। उसके पति महोदय एक अरसे से पत्नी से मिलने का अरमान संजोये जब घर पधारे, तो पता चला कि उनकी पत्नी ने तो डाकिये से शादी रचा ली है।

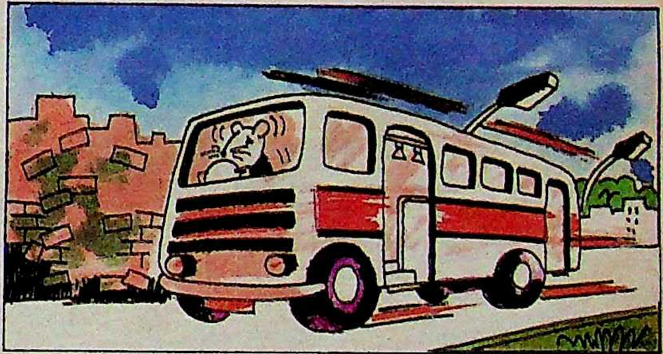

उग्रवादी चूहे

अभी तक तो चूहे घरों में घुसकर बेशकीमती कपड़े काटने या आफिसों में घुसकर आलमारियों में रखे कागजात कुतरकर किसी कर्मचारी को सांसत में डालने के लिए बदनाम रहे हैं, लेकिन वे अब यदि बसें भी स्टार्ट कर ले जाने में सफल हैं, तो कोई क्या कर ले। हुआ यह कि दिन भर की ड्यूटी के बाद एक प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर पंजाब के नूरमहल बस अड्डे पर अपनी बस खड़ी कर उसी में सो रहे थे कि एकाएक बस स्टार्ट होकर चल पड़ी। दोनों ऊंघते-ऊंघते उठे और उग्रवादी-उग्रवादी कहकर चिल्लाने लगे। बस थी कि डिपो से निकल नगरपालिका की दीवार तोड़ती पार्क में निकल गयी, लेकिन थोड़ा आगे जाकर अपने आप रुक गयी। इतने में वहां काफी लोग इकट्ठा हो गये। जब लोगों ने जांच-पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि कुछ चूहे खाने की तलाश में बस में घुसे थे और उसके सेल्फ के तारों को छेड़ने लगे थे। बस गियर में खड़ी थी, सो तार खिंचते ही स्टार्ट होकर चल पड़ी थी।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

बंबई पर दक्षिण की सिने महारानियों का वर्चस्व

बंबई फिल्म इंडस्ट्री ने यों तो एक-से-एक प्रतिभाशाली हीरोइनों को पैदा किया, लेकिन नर्गिस के बाद किसी भी हीरोइन को 'नंबर एक' का खिताब हासिल नहीं हुआ। उस पर हमेशा दक्षिण से आयी हीरोइनों का ही कब्जा रहा। दक्षिण की हीरोइनों में ऐसी कौन सी खासियत है कि वे बंबई की हीरोइनों को पीछे छोड़ जाती हैं ?

तीन दशक पहले जब स्व० नर्गिस ने 'मदर इंडिया' के प्रदर्शन के बाद फिल्मों में अभिनय से सक्रिय रूप से संन्यास ले लिया था और सिर्फ अपने भाई की फिल्म 'आधा दिन आधी रात' की शूटिंग पूरी की थी, तो स्व० महबूब खां ने कहा था, "अब बंबई की कोई अभिनेत्री नंबर-वन नहीं बन सकेगी। नंबर-वन बनने का जो माद्दा, शख्सीयत तथा विशिष्टता एक अभिनेत्री में होनी चाहिए, वह न तो वर्तमान अभिनेत्रियों में मौजूद है और न ही आनेवाली पीढ़ी अपने भीतर वह बात पैदा कर सकेगी।" स्व० महबूब ने जब यह बात कही थी, उस समय निम्मी, मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, सुरैया, बीना राय, गीताबाली, नलिनी जयवंत लोकप्रियता के शिखर पर थीं और वैजयंतीमाला, पद्मिनी, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, अमीता, अनीता गुहा, शर्मिला टैगोर, श्यामा आदि अभिनेत्रियों ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत की थी।

और स्व० महबूब की मजाक में कही गयी वह बात सचमुच की भविष्यवाणी साबित हुई—नर्गिस के बाद नंबर-वन की बादशाहत जो दक्षिण की अभिनेत्रियों ने हथियायी, वह आज तक वर्तमान है। इन तीन दशकों की अवधि में इस बादशाहत को प्राप्त करने के लिए बंबई की अभिनेत्रियों ने काफी कोशिश की, वहां की अभिनेत्रियों के मुकाबले बेहतरीन तथा बाक्स आफिस पर ज्यादा सुपर हिट फिल्में दीं, लेकिन वे नंबर-दो से आगे नहीं बढ़ सकीं।

स्व० नर्गिस के संन्यास से रिक्त नंबर-वन का स्थान वैजयंतीमाला ने १९५७ में सहज ही प्राप्त कर लिया था। सहज ही इसलिए कि उनकी पहली ही फिल्म 'बहार' (१९५१) बाक्स आफिस पर सुपरहिट रही थी। १९५१ से १९५७ के छह वर्षों के अंतराल में 'अंजाम' (१९५२) को छोड़कर 'लड़की' (१९५३), 'नागिन', 'पहली झलक' तथा 'मिस माला' (१९५४), 'देवदास' (१९५५), 'देवता', 'नयी दिल्ली', 'पटरानी' (१९५६) ने अप्रतिम व्यावसायिक सफलता हासिल कर वैजयंतीमाला को प्रथम पंक्ति का सितारा बना दिया था। वैजयंतीमाला की सफलता के आगे नूतन, माला सिन्हा, गीताबाली, मीना कुमारी, बीना राय, मधुबाला, सुचित्रा सेन, पद्मिनी, नलिनी जयवत, और निम्मी जैसी अभिनेत्रियां अपने पांव नहीं जमा सकीं। १९५८ तो वैजयंतीमाला के अभिनय कैरियर में मोड़ बनकर आया।

अप्रतिम सफलता : इस दौरान वैजयंतीमाला को मिली इस अप्रतिम सफलता से प्रभावित हो दक्षिण सिनेमा की जानी-मानी कई अभिनेत्रियों ने भी बंबइया फिल्मों में अपना स्थान बनाने की कोशिश की, लेकिन वहीदा रहमान, अंजलि देवी, बी सरोजा देवी विशेष सफल नहीं हो सकीं, फलतः वे वापस मद्रास लौट गयीं। वहीदा रहमान के अलावा पद्मिनी को एक हद तक सफलता मिली। उन्होंने बाद में 'जिस देश में गंगा बहती है', 'आशिक', 'मेरी बहन', 'मेरा नाम जोकर' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन दक्षिण से ही आयी वहीदा रहमान ने काफी तेजी से प्रगति की। उन्होंने 'बात एक रात की', 'बीस साल बाद', 'राखी', 'साहब बीवी गुलाम', 'एक दिल सौ अफसाने', 'कोहरा', 'मजबूर', 'शगुन', 'दिल दिया दर्द लिया', 'गाइड', 'पत्थर के सनम', 'राम और श्याम', 'नील कमल', 'आदमी' आदि फिल्मों में काम कर नंबर-वन के समानांतर अपना स्थान बना लिया, लेकिन नंबर-वन रहीं सिर्फ वैजयंतीमाला।

इस दौरान वैजयंतीमाला को पुरानी पीढ़ी की अभिनेत्रियों-सुरैया से लेकर मीना कुमारी तक के वर्चस्व एवं लोकप्रियता का जहां सामना करना पड़ा, वहीं उन्हें नयी पढ़ी की अभिनेत्रियों (साधना, आशा पारिख, शर्मिला टैगोर, राजश्री, माला सिन्हा, मुमताज आदि) को मिली अपार लोकप्रियता, स्टारडम के कारण उत्पन्न खतरों का भी सामना करना पड़ा और वहां भी वे अपना नंबर-वन स्थान बनाये रखने में सफल रहीं।

नयी पीढ़ी की उपरोक्त अभिनेत्रियों की लोकप्रियता एवं स्टारडम की चुनौती के दौरान ही १९६७ में हेमामालिनी ने जब 'सपनों का सौदागर' से कदम रखा था, तब किसी को भी इस बात का अहसास नहीं था कि वे शर्मिला टैगोर, आशा पारिख, मुमताज का सामना कर सकेंगी। १९६९ में जब हेमा की दो हलकी फिल्में 'वारिस' और 'जहां प्यार मिले' प्रदर्शित हुई थीं, तो उसी समय शर्मिला टैगोर की 'आराधना', मुमताज की 'जिगरी दोस्त', 'बंधन' तथा 'दो रास्ते', साधना की 'एक फूल दो माली, पद्मिनी की 'चंदा और बिजली', वहीदा रहमान की 'खामोशी' तथा 'मेरी भाभी' जैसी सफल फिल्में प्रदर्शित हुई। ठीक दूसरे वर्ष, १९७० में रेखा

वैजयंतीमाला छाया : फालएस गिरोटा

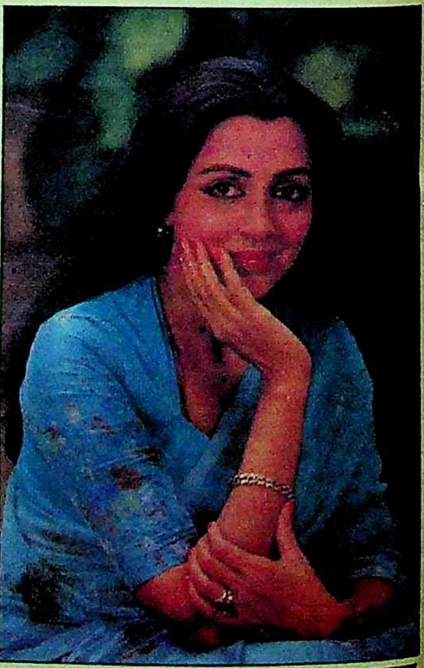

हेमामालिनी छाया : बालकृष्ण

(सावन भादों) तथा १९७१ में जीनत अमान (हरे राम हरे कृष्ण एवं हलचल) का आगमन हुआ, जो आगे चलकर उनके लिए जबर्दस्त चुनौती साबित हुई—खूबसूरती में भी और ग्लैमर में भी। लेकिन १९७० हेमामालिनी के लिए विलक्षण साबित हुआ, जब उनके कैरियर और जिंदगी को दो विविध आयाम मिले। एक तरफ उनकी 'शराफत', 'जानी मेरा नाम' जैसी सुपरहिट फिल्मों के अलावा 'जहां प्यार मिले' तथा 'तुम हसीं मैं जवां' जैसी फिल्में आयी, तो दूसरी तरफ 'शराफत' एवं 'तुम हसीं मैं जवां' में उन्होंने उस धर्मेंद्र के साथ पहली बार काम किया, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी के भी हमसफर बन गये। एक दशक के काल में धर्मेंद्र-हेमामालिनी की जोड़ी दूसरी सभी जोड़ियों से कहीं अधिक लोकप्रिय रही।

रेखा छाया: बघु बन्ना

जयाप्रदा

श्रीदेवी छाया: तैयब बादशाह

१९६८ से १९७० जहां हेमामालिनी के कैरियर का उदय का काल था, वहीं नंबर वन वैजयंतीमाला की विदाई का भी काल साबित हुआ। उनकी १९६८ में 'दुनिया', 'साथी', 'आदमी', १९६९ में 'प्रिंस' तथा 'प्यार ही प्यार', १९७० में 'गंवार' आयी। इसी वर्ष वैजयंतीमाला ने फिल्मों से संन्यास ले लिया और नर्गिस से पायी नंबर वन की सत्ता हेमामालिनी ने पा ली जिस पर वे डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक बरकरार रहीं।

व्यावसायिक राजनीति: हेमामालिनी के वर्चस्व को खतम करने की जितनी कोशिश जीनत अमान ने की, उतना किसी और अभिनेत्री ने वैजयंतीमाला की सत्ता के पाये को खिसकाने के लिए नहीं किया। हेमामालिनी के समय में अभिनेत्रियों ने 'व्यावसायिक राजनीति' का जो फार्मूला शुरू किया, वह आज चरम परिणति के रूप में पहुंच गया है। लेकिन हेमा के उत्कर्ष काल में ही जीनत का ग्लैमर धीरे-धीरे बीते हुए कल की बात हो गया और उसे ग्रहण किया दक्षिण की ही रेखा ने। उस समय सुपर स्टार बन गये अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बनी जोड़ी ने उन्हें वहीदा रहमान की-सी स्थिति में पहुंचा दिया, जो उन दिनों वैजयंतीमाला के समानांतर चल रही थीं।

१९८० में हेमा के बढ़ते पराभव तथा रेखा के बढ़ते प्रभाव से एकबारगी लगा कि रेखा नंबर-वन बन जायेंगी, लेकिन दो वर्ष बाद श्रीदेवी (सोलहवां सावन) ने अचानक बंबइया फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया और दूसरे वर्ष १९८३ में हवा का रुख ही जैसे पलट दिया। इसके पूर्व दक्षिण से जयाप्रदा (सरगम) पहले ही आ कर रेखा के लिए खतरा बन चुकी थीं। उनमें रेखा से अधिक नैसर्गिक रूप लावण्य तो था ही, वे डांसिग स्टार भी थीं। फिर 'सिलसिला' के बाद अमिताभ बच्चन का साथ छूट जाने पर रेखा के लिए अकेले संघर्ष करना संभव भी नहीं रहा था, इसीलिए इस दरम्यान बेहतरीन फिल्में करने के बावजूद जबरन उन्हें पूर्ववत तीसरे स्थान पर आ जाना पड़ा—दूसरा स्थान दक्षिण की ही जयाप्रदा को मिल गया।

१९८३ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ताजगी लेकर आया। एक तरफ श्रीदेवी को स्टारडम के शिखर पर स्थापित कर देनेवाली 'हिम्मतवाला' तथा 'सदमा' जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं, तो उसी वर्ष मीनाक्षी शेषाद्रि हीरोइन से स्टार बन गयीं। इस वर्ष रामायण की सीता उर्फ दीपिका (सुन मेरी लैला) तथा माधुरी दीक्षित (अबोध) भी फिल्म इंडस्ट्री में आयीं। अपने अस्त होते कैरियर में जीनत (जमाना, जानवर, पुकार) ने वापसी की असफल कोशिश की, लेकिन हेमामालिनी (जस्टिस चौधरी, तकदीर, अंधा कानून, नास्तिक, रजिया सुलतान) अपने वर्चस्व को एक हद तक बनाये रखने में सफल रहीं।

अपनी खूबसूरती के बावजूद जयाप्रदा श्रीदेवी के ग्लैमर का सामना नहीं कर पायीं। 'मवाली' आदि कई फिल्मों में दोनों ने साथ-साथ काम किया, लेकिन हर जगह श्रीदेवी का ग्लैमर स्टारडम की दौड़ में अगुवाया रहा। इस दौरान दक्षिण से माधवी, स्वप्ना, राधिका फिर भानुप्रिया आयीं। भानुप्रिया के आगमन ने श्रीदेवी के स्टारडम को जिस तेजी से धुंधलके में डाला था, उसी तेजी से धुंधलके का कोहरा भी छंट गया। एक बार उन्हें दक्षिण से ही आयी रति अग्निहोत्री (एक दूजे के लिए) से भी खतरा उत्पन्न हुआ था, लेकिन गलत फिल्मों के चुनाव के कारण रति दौड़ में आगे आकर भी पिछड़ गयी। ऐसे ही हालात से दक्षिण से आयी फरहा को भी गुजरना पड़ा और वे दूसरी प्रांत की अभिनेत्री भर बनकर रह गयीं। दक्षिण की ही अमला के साथ भी ऐसा ही हुआ।

स्टारडम को चुनौती : पिछले वर्ष जिस तरह से रेखा अपनी फिल्मों 'खून भरी मांग,' 'बीवी हो तो ऐसी,' 'इजाजत' से वापस आयी हैं, उससे श्रीदेवी के स्टारडम को धक्का लगा है, जिस पर वे पिछले पांच वर्षों से जमी हुई हैं।

दक्षिण के 'स्टार-मेकर' निर्देशक के राघवेंद्र राव, जिन्हें श्रीदेवी को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय है, 'माया' को बतलाते हैं, "नहीं, रेखा या भानुप्रिया से श्रीदेवी को कोई खतरा नहीं—श्रीदेवी की स्थिति ठीक अमिताभ बच्चन की तरह है, जिनकी फिल्मों के पिटने के बावजूद उनकी मांग तथा मार्केट-रेट में कमी आने के बजाय वृद्धि ही हुई है।"

तीन दशकों के लंबे दौर में नंबर वन की सत्ता जो बंबइया फिल्म अभिनेत्रियों के नियंत्रण से खिसक कर दक्षिण की अभिनेत्रियों के हाथ में चली गयी, उसका कारण क्या है, मीना कुमारी से लेकर शबाना आजमी तक बेहतरीन अभिनेत्रियों के होने के बावजूद यह सत्ता-नियंत्रण बंबई वापस क्यों नही लौट सका? इसका जवाब के बापैया देते हैं, "दक्षिण की अभिनेत्रियां अनुशासनबद्ध अपने काम-से-काम रखनेवाली तथा जरूरत की हद तक निष्ठावान होती हैं। वे अकेले दम निर्णय लेने की हिम्मत रखती हैं।" जीतेंद्र के अनुसार वे 'फ्लेक्सेबुल' तथा 'बेहतरीन कोआपरेटिव' होती हैं।

नर्गिस के बाद नंबर वन जब वैजयंतीमाला हुई थीं, तो नंबर दो दक्षिण की ही वहीदा रहमान तथा नंबर तीन पद्मिनी थीं। हेमामालिनी के जमाने में यह क्रम थोड़ा बदल कर जीनत अमान तथा रेखा के हक में गया और अब श्रीदेवी के दौर में पुनः नंबर दो, तीन, चार दक्षिण की ही जयाप्रदा, रेखा तथा मीनाक्षी शेषाद्रि के हक में चला गया। सिर्फ डिंपल कपाड़िया नंबर दो तक पहुंच पायीं, लेकिन नंबर एक बनने की उनकी दुर्लभ आकांक्षा धरी-की-धरी रह गयी।

—रवींद्र श्रीवास्तव

आमीर खान और एकता छाया: बिमोर

एकता की मासूमियत

देवआनंद की नयी खोज—१६ वर्षीय एकता इतनी भोली हैं कि उन्हें पृथ्वीराज कपूर खानदान में सिर्फ राज अंकल और ऋषि कपूर के बारे में ही जानकारी है। स्व० के आसिफ, बिमल राय और सोहराब मोदी का नाम तो एकता ने नहीं सुना, लेकिन बेचारे राजेश खन्ना के दिल पर क्या बीती होगी, जब एकता ने काका की मौजूदगी में ही कह दिया कि राजेश खन्ना कौन हैं? लेकिन राजेश खन्ना भी ठहरे राजेश खन्ना जो एकता की मासूमियत पर इस कदर फिदा हुए कि अपने स्टोरी राइटर को बुलाकर उन्होंने एक लवस्टोरी लिखने का हुक्मनामा थमा दिया जिसकी हीरोइन एकता होंगी, हीरो वे खुद होंगे तथा खलनायक की भूमिका निभायेंगे आमीर खान, जिन्हें एकता 'दुनिया का सबसे स्मार्ट अभिनेता' मानती हैं।

अब कहीं शूटिंग के दौरान एकता राजेश खन्ना को राजेश अंकल कह बैठें तो?

किरण का गंगावतरण

जुहू तट पर स्थित एक पंचसितारा होटल के हरी घासोंवाले विशाल लान में 'बंटवारा' फिल्म की चल रही पार्टी में मौजूद लगभग तीन हजार फिल्मवालों की निगाहें एक लड़की पर ठिठक गयीं। जब विनोद खन्ना से नहीं रहा गया, तो उन्होंने अमृता सिंह से पूछ ही लिया, "कौन है यह लड़की? बिलकुल अप्सराओं जैसी लग रही है?" तब अमृता सिंह ने अपनी नाजानकारी जाहिर की। उसे उसी अंदाज में शम्मी कपूर, मोहसिन ख़ान आदि ने भी दुहरा दिया। इस पर पास खड़ा एक फिल्म निर्माता भाग कर उस लड़की को बुला लाया और विनोद खन्ना से उसका परिचय कराते हुए बोला, "ये जी किरण जुनेजा हैं जी! वही 'बुनियाद' और 'महाभारत' वाली! 'महाभारत' में ये गंगा बनी थीं जी।" उसकी बात खतम भी नहीं हुई थी कि पास खड़ी 'बुनियाद' वाली नीना गुप्ता चुटकी लेती हुई बोलीं, "गंगावाली! तभी गंगा का ही कास्ट्यूम पहन कर आ गयी हैं इस फिल्मी महाभारत (पार्टी) में!"

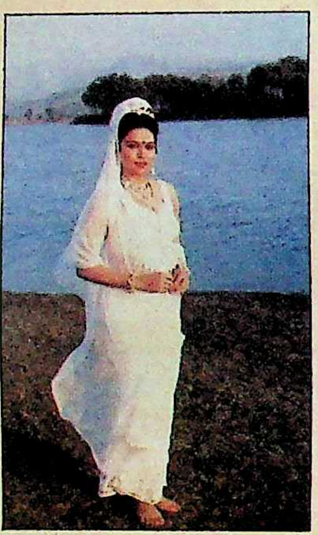

किरण जुनेजा

दूरदर्शन के नाम से तौबा करने तथा अपने को ही सिर्फ फिल्म स्टार माननेवाली किरण जुनेजा ने नीना गुप्ता की टिप्पणी सुनी या नहीं, पता नहीं, लेकिन महाभारत में गंगा की भूमिका में वे जो परिधान धारण किये हुए थीं, उससे वे इतना प्रभावित हुई थीं कि उन्होंने ठीक वैसा ही, लेकिन रंग-बिरंगा परिधान खास पार्टियों में पहनना शुरू कर दिया है।

राज बब्बर का सच

असंतुष्टों-बिगड़ैलों को समेटने-जोड़ने का जो काम वीपी सिंह अपनी राजनीतिक दुनिया में कर रहे हैं, तकरीबन कुछ वैसा ही काम उनके फिल्मी शिष्य राज बब्बर फिल्मी दुनिया में कर रहे हैं। उनका मानना है कि श्रीदेवी (तमिलनाडु चुनाव), अरुण गोविल (इलाहाबाद उपचुनाव), सुनील दत्त व राजेश खन्ना (विलेपार्ले—बंबई उपचुनाव) की स्टारडम की चमक इन चुनावों में इसलिए धूमिल नहीं हुई कि उनकी चमक में दमखम नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने गलत पार्टी का पल्ला पकड़ा था।

राज बब्बर ने सुनील दत्त को एक नेक सलाह दी है कि अगले आमचुनाव में जमानत रद्द होने का अपमान न सहना पड़े, इसलिए वे अभी से जनता दल में शामिल हो जायें। अब अगर उनकी सलाह पर अमिताभ बच्चन भी अमल कर लें, तो अगला कदम क्या होगा वीपी सिंह और राज बब्बर का? इसका जवाब वे नहीं देते!

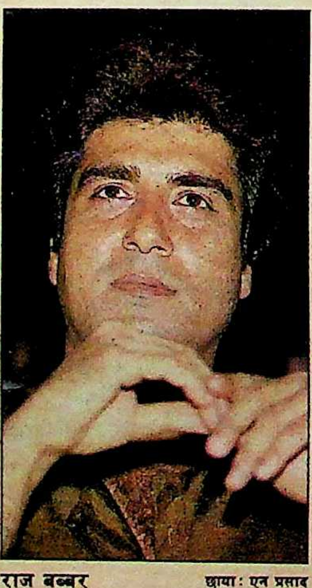

राज बब्बर छाया: एन प्रसाद

चुंबन का करिश्मा

जिन उत्तेजक चुंबनों का सहारा लेकर यश चोपड़ा न तो अपनी फिल्म 'विजय' को जय दिला सके थे और न ही सोनम अपनी साख को गिरने से बचा सकी थीं, उसी चुंबन ने आसिफ नामक एक नौसिखिये कलाकार को रातोरात सितारा बना दिया। 'लव स्टोरी' जैसी बाक्स आफिस हिट फिल्में लिखनेवाले मिर्जा ब्रदर्स ने आसिफ तथा किमी कातकर के अंतहीन चुंबन दृश्यों को अपनी फिल्म 'रामा ओ रामा' में फिल्माकर नये कीर्तिमान बनाने की कोशिश की। कीर्तिमान की बात तो आसिफ और किमी कातकर ही जानें, क्योंकि बहुत से चुंबन दृश्य सेंसर बोर्ड को कुछ इस हद तक नागवार गुजरे की उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उन पर कैंची चला दी।

आसिफ और सोनू वालिया छाया: डीआर यादव

बहरहाल फिल्म तो नहीं उबर सकी, लेकिन किमी जरूर उबर गयीं और उन्होंने फिल्में साइन करने का कीर्तिमान भी कायम कर लिया। रहे आसिफ मियां, तो उन्होंने निर्माताओं से कहना शुरू कर दिया है कि जिसे भी हीरोइन लो, उसे जतला दो कि उसे चुंबन दृश्य देने ही पड़ेंगे। अब उनकी बात का असर सोनू वालिया पर कितना हुआ है, यह बाद की बात है!

—अखबारी लाल

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा मया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस, ३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

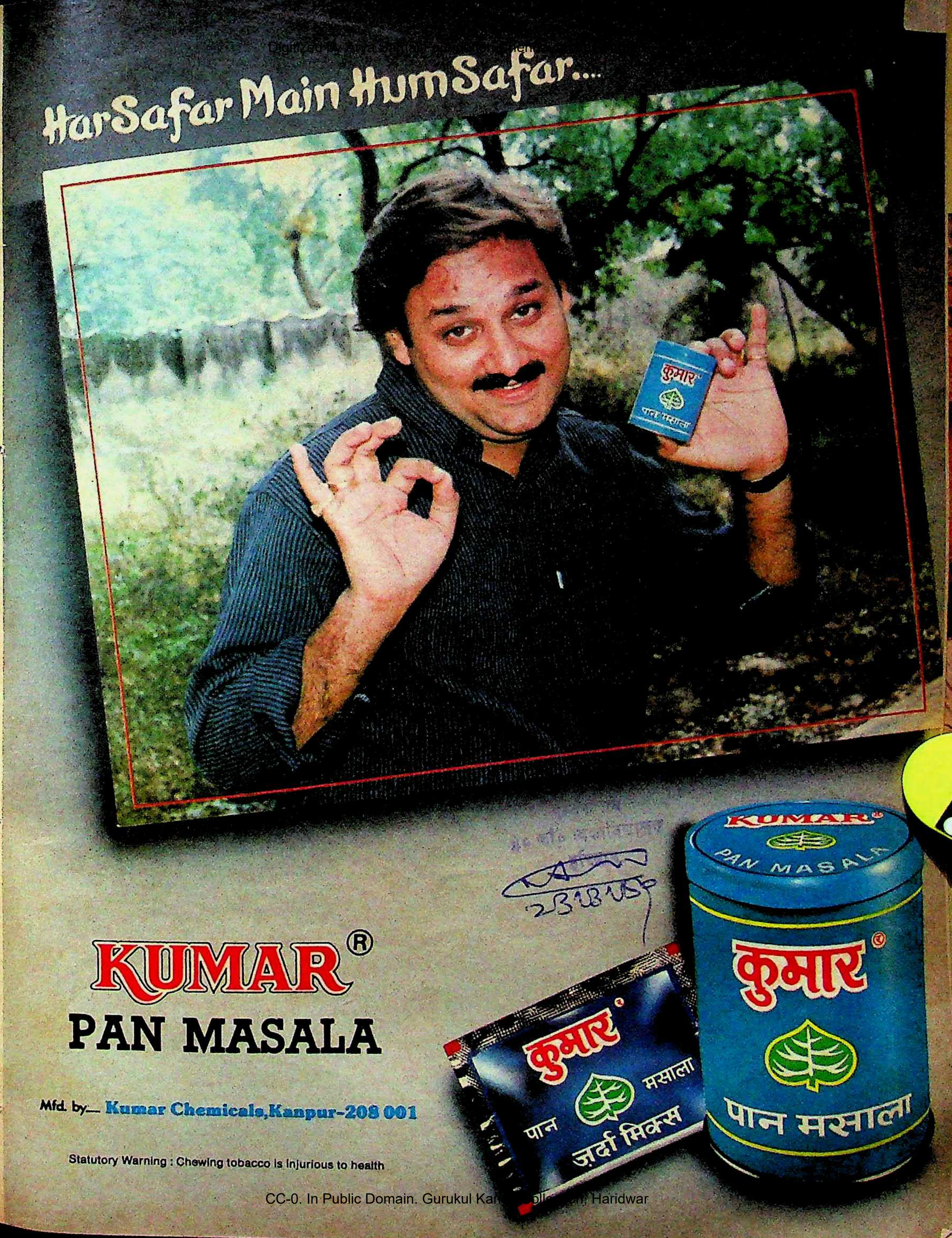
Har Safar Main Hum Safar....
कुमार
पान मसाला
KUMAR®
PAN MASALA
कुमार
पान मसाला
कुमार
पान मसाला
ज़र्दा मिक्स

KUMAR®

PAN MASALA

Mfd. by— **Kumar Chemicals, Kanpur-208 001**

Statutory Warning : Chewing tobacco is injurious to health

बचाव कार्य में सफलता ने दिया वो चैन और संतोष भरा अहसास
जो मुझे मिलता है
अपनी मनपसंद रेड एण्ड व्हाईट किंग्ज़ के साथ।
You can't beat the feeling
RED & WHITE
KINGS
MADE IN INDIA
RED & WHITE
KINGS
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
अब नए पैक में।
वैधानिक चेतावनी:
सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।
everest/d88/HMA/395 hn

CC-0. In Public Domain. ... Collection, ...idy...

माया

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ६०, अंक ६   ३१ मार्च, १९८९

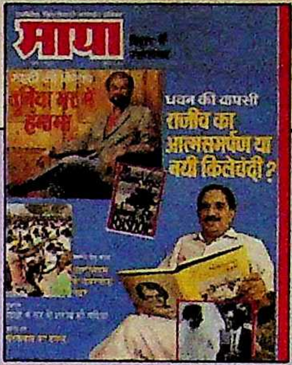

आवरण कथा

२९

गजब की सूझबूझ, निष्ठा और तत्परता के साथ २२ वर्षों की सत्ता-सेवा के बदौलत स्व० इंदिरा गांधी की हैसियत का अभिन्न अंग बन चुके आरके धवन, राजीव गांधी के सत्ता में आते ही बड़े बेआबरू होकर सत्ता के गलियारे से निकले थे। अब चार साल के बाद राजीव गांधी ने आरकेधवन को अपना खासमखास बना लिया है। धवन को वापस लेने के पीछे क्या विवशता थी?

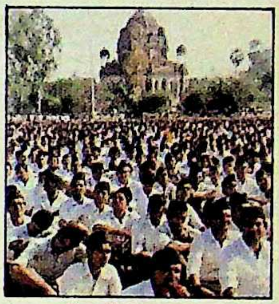

१७ हिंदू संगम

लखनऊ में आयोजित 'हिंदू संगम' ने आरएसएस को जो विशेष भूमिका सौंपी, उसके नतीजे क्या-क्या हो सकते हैं?

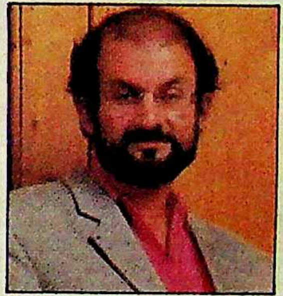

४१ रुश्दी

सलमान रुश्दी ने 'द सेटेनिक वर्सेज' में ऐसा क्या लिख दिया, जिसे लेकर दुनियाभर में बावेला मचा हुआ है?

७६ बिहार में तख्तापलट

बिहार के राजनीतिक संकट की आड़ में मुख्यमंत्री और केंद्रीय काबीना के बिहारी अखाड़ियों के एकमुश्त इस्तीफे क्यों?

७० गुजरात

महात्मा गांधी का जन्मदाता राज्य गुजरात जहरीली शराब कांडों का शिकार क्यों होता रहा है?

४९ बिहार और विपक्ष

बिहार 'जद' प्रमुख के पद पर रघुनाथ झा की नियुक्ति को लेकर पूरी पार्टी में उबाल आ गया—आखिर क्यों?

९४ फिल्म

समांतर सिनेमा से व्यावसायिक सिनेमा तक धूम मचानेवाले नसीरुद्दीन शाह के फिल्मी कैरियर का लेखाजोखा।

देश : जनता दल : घटकवाद की घुटन २३
प्रसंगवश : भोपाल गैस कांड : समझौता या सौदा? २६
आवरण कथा : धवन को क्या करना है? ३७
आवरण कथा : धवन को क्यों निकाला गया था? ३९
खेल : भारत-वेस्टइंडीज दौरा : ऊंट किस करवट बैठेगा? ४६
राजस्थान : सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री : पांच हजार मजदूर निर्णायक लड़ाई में ५२
राजस्थान : रामलाल मीणा : दोषी या जातीय भेदभाव के शिकार? ५४
गुजरात : अब कैसे बचेंगे अमर सिंह चौधरी? ५८
केरल : बेरोजगारी : खाड़ी देशों की ओर भागते लोग ६१
उत्तर प्रदेश : रेलजाम ने सरकार को झुकाया! ६४
असम : बोडोलैंड आंदोलन : क्षेत्रीयतावाद का एक और नासूर ६६
दूरदर्शन : 'टीपू सुल्तान' का दुर्भाग्य! ८३
विदेश : पणछेन लामा का निधन : क्या चीन का रुख बदलेगा? ८९
स्त्री : वसंत साठे उवाच! ९२

आवरण पारदर्शी
अविनाश पसरीचा
(धवन)
राजेंद्र कुमार
(हिंदू संगम)

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
ब्यूरो प्रमुख
बंबई : रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ : अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना : विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ : सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल : सुधीर सक्सेना
जयपुर : ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

० प्रधान कार्यालय : २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन : ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स : ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय : ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन : ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स : ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय : बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन : ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय : ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन : २६७४०, भोपाल कार्यालय : एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन : ६६३८८, बंबई कार्यालय : ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन : २४३५७७, तार : माया कहानी, टेलेक्स : ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय : स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन : २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©

इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

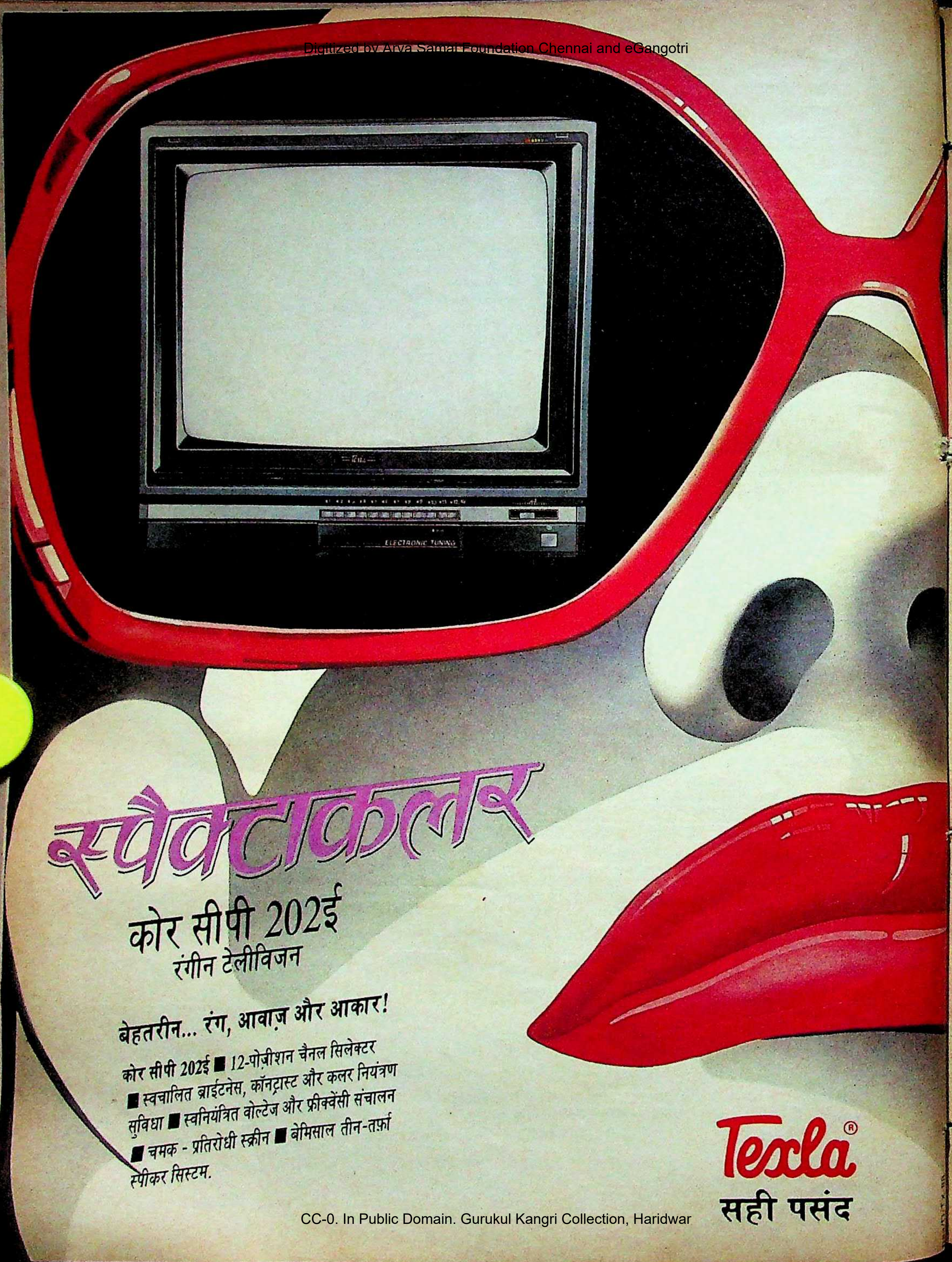

स्पैक्टाकलर

कोर सीपी 202ई

रंगीन टेलीविजन

बेहतरीन... रंग, आवाज़ और आकार!

कोर सीपी 202ई ■ 12-पोज़ीशन चैनल सिलेक्टर ■ स्वचालित ब्राईटनेस, कॉनट्रास्ट और कलर नियंत्रण सुविधा ■ स्वनियंत्रित वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी संचालन ■ चमक - प्रतिरोधी स्क्रीन ■ बेमिसाल तीन-तर्फ़ा स्पीकर सिस्टम.

Texla®

सही पसंद

क्या सलाहकारों ने पैदा किया ?
क्या विपक्ष इसका फायदा उठायेगा ?

राजीव का संकट क्या उनके सलाहकारों ने पैदा किया है ?

'माया' का ताजा अंक मिला। आवरण कथा 'क्या राजीव का संकट उनके सलाहकारों ने पैदा किया है ?' पढ़ी। इस कथा से तो यही प्रतीत होता है कि राजीव गांधी के जो खासमखास लोग हैं, जो अपने को उनकी नाक का बाल कहते हैं, वे ही उनके लिए सबसे बड़े अपशकुन सिद्ध हो रहे हैं। यदि इन सलाहकारों का यही रवैया रहा, तब तो बेचारे राजीव गांधी की कांग्रेसी नैया को हिचकोले खाने से कोई नहीं बचा सकता। कम-से-कम राजीव गांधी को गुलाम नबी आजाद, बूटा सिंह, शीला दीक्षित और माखनलाल फोतेदार जैसे सलाहकारों से सावधान हो जाना चाहिए, वर्ना ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा के चलते जहां कांग्रेस की साख है, वहां भी लकड़ी लगाकर रहेंगे। **—कुमार आनंद, १३ सी, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली**

कांग्रेस में खुली बगावत

'माया' (२८ फरवरी '८९) में प्रकाशित आवरण कथा 'कांग्रेस में खुली बगावत' पढ़कर लगा कि यह सब केवल कुरसियों की स्वार्थभरी उठा पटक है, जो कांग्रेस की छवि को धूमिल करती लग रही है। यह स्थिति कांग्रेस की ही नहीं, देश के अन्य सभी दलों की भी है। पक्ष-विपक्ष दोनों में चल रही इस भितरघात की तुलना में कांग्रेस अभी भी देश की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी है। जहां तक उसमें बागियों का सवाल है, तो वे अपने ही जाल में फंसकर धराशायी होंगे। वे आखिर दिल्ली के अंकुश से बचकर जायेंगे कहां ? कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में जाने से जो तबाही उनके पल्ले पड़ेगी, उसका भय उन्हें है। वे डाल के चूके बंदर कभी नहीं बनना चाहेंगे, यह बात राजीवजी जानते हैं। **—मुकुंददास माहेश्वरी, डीबी बल्लभदास पैलेस जबलपुर, मध्य प्रदेश**

अर्जुन सिंह कैसे गये, वोरा कैसे आये ?

२८ फरवरी के अंक में 'अर्जुन सिंह कैसे गये, वोरा कैसे आये ?' लेख से साफ जाहिर होता है कि हमारे देश की राजनीति घटिया स्तर तक पहुंच चुकी है एवं प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। लेख से यह भी जाहिर होता है कि वोराजी को योग्यता के बल पर नहीं लाया गया है, बल्कि दो की लड़ाई में तीसरे व्यक्ति का फायदा वाली बात चरितार्थ होती है। कई घंटों तक चलने वाली रस्सा-कसी से भूतपूर्व मुख्यमंत्री की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। **—नवींद्र ठाकुर, बालाघाट**

सुब्रह्मण्यम स्वामी का खेल

२८ फरवरी की 'माया' में 'सुब्रह्मण्यम स्वामी का खेल' पढ़ी। डा० स्वामी द्वारा हेगड़े पर निराधार लगाये आरोपों से स्वामी की ही इज्जत गिरी है। अगर हेगड़े दोषी हैं, तो स्वामी अदालत में क्यों नहीं जाते ? स्वामी ने तो उसी थाली में छेद किया है, जिसमें खाया था। **—छोटूराम लेगा, ग्राम खैरवा डेगाना, राजस्थान**

क्या मृत्युदंड इसका इलाज है ?

'माया' (२८ फरवरी) में प्रकाशित रिपोर्ट 'क्या मृत्युदण्ड इसका इलाज है' पढ़ी। लेखक व विभिन्न व्यक्तियों के मतानुसार नशीले पदार्थों के व्यापार को वैध बना देना चाहिए। यह तर्क सही भी है, शायद यह उपाय ही नशावृत्ति की बढ़ती हुई समस्या का समाधान कर सके। लोकसभाध्यक्ष बलराम जाखड़ का यह वक्तव्य कि अवैध व्यापार करने वालों को तुरंत गोली से उड़ा देना चाहिए, जमा नहीं। **—शैलेन्द्र रोहतगी, भैरोनाथ, वाराणसी**

'क्या मृत्यु दण्ड इसका इलाज है' को पढ़कर लगा कि शायद इन नशीले पदार्थों का सरकारीकरण ही उचित समाधान है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह जरूरी नही कि इन पदार्थों के सरकारीकरण से इसके व्यसनियों की बढ़ती संख्या पर रोक लगेगी या उसमें स्वयमेव ही कमी आ जायेगी। शायंद इसीलिए कि नशेड़ियों के खुले रूप से उजागर हो जाने के डर से, वे लोग इनका प्रयोग कम कर देंगे। इसमें संदेह है, क्योंकि अपराधी बेशक नशेबाज हो या चोर उच्चका, उसे अपनी बेइज्जती की चिंता रहती ही कहां है ?

अत: इसके लिए आवश्यकता है इन नशीले पदार्थों के धंधे में लिप्त अपराधियों के विनाश (समाप्तीकरण) की, जो मात्र कानून बना देने से संभव नहीं, बल्कि ईमानदारी, दृढ़ता व कठोरता से उन्हें दण्डित करवाकर फांसी के फंदों तक पहुंचाने से ही फलीभूत हो सकेगा, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। **—तारा चंद 'देव', पूर्व सचिव राजस्थानी कल्याण परिषद्, हरिद्वार**

जिम्मेदार कौन ?

'माया' के २८ फरवरी '८९ के अंक में 'जिम्मेदार कौन ?' के तहत हिंदू-सिख दंगों का जो वर्णन हुआ है, उससे मानसिकता के रुग्ण रुख का पता चलता है। वस्तुत: अपराध जगत और पुलिस प्रशासन का संबंध 'तू डाल-डाल, मैं पात-पात' वाला है और रुग्ण मानसिकता के यथावत कायम रहते इस स्थिति पर नियंत्रण पाना नामुमकिन सा है। राष्ट्र विकास के जिस दौर से गुजर रहा है, उस दौर में ऐसी मानसिकता अत्यंत घातक है। दरअसल हिंदू सिख मनमुटाव की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है और यदि इस बात को नजरअंदाज न किया जाये, तो वर्तमान में घटने वाले समस्त दंगों की जड़ अवसरवादियों की लोलुपता है। इतिहास गवाह है कि कूटनीति एवं राजनीति के क्षेत्र में शिकस्त खायें हुए खिलाड़ी धर्म और संप्रदाय के सहारे अपनी दाल गला पाने में कामयाब होते हैं। अत: इन दंगों पर काबू पाने के लिए यह नितांत आवश्यक

रजिस्ट्रेशन आफ न्यूज पेपर्स (सेन्ट्रल) नियम १९५६ के ८वें नियम के अन्तर्गत 'माया' नामक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रकाशित किया जाने वाला विवरण :

फार्म. ४

१. प्रकाशन का स्थान —१६६, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।
२. प्रकाशन का अवधिक्रम —पाक्षिक
३. मुद्रक का नाम —श्री वीरेन्द्रनाथ घोष
राष्ट्रीयता —भारतीय।
पता —१६४, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।
४. प्रकाशक का नाम —मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड।
राष्ट्रीयता —भारतीय।
पता —१६६, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।
५. सम्पादक का नाम —श्री आलोक मित्र।
राष्ट्रीयता —भारतीय।
पता —१ ए, हाशिमपुर रोड, इलाहाबाद।
६. उन शेयर होल्डरों के नाम और पते जिनके पास कुल पूंजी के १ प्रतिशत से अधिक के शेयर हैं :—
श्रीमती नन्दरानी मित्र,
१ ए, हाशिमपुर रोड, इलाहाबाद।
श्री वीरेन्द्रनाथ घोष
१६४, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।
श्री आलोक मित्र,
श्री अशोक मित्र,
श्री दीपक मित्र,
श्री मनमोहन मित्र
१ ए, हाशिमपुर रोड, इलाहाबाद।

मैं, वीरेन्द्रनाथ घोष, वास्ते मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, यह घोषित करता हूं, कि ऊपर दिये गये विवरण, जहां तक मैं जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य हैं।

प्रकाशक के हस्ताक्षर : वीरेन्द्रनाथ घोष
वास्ते मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद
३१ मार्च, १९८९

है कि जनशक्ति प्रशासन के साथ पूर्णतः सहयोग करे और छोटी चिगारियों को शोला बनने के पूर्व ही यथासभव शांत करने की चेष्टा करे।—**जयंत चक्रवर्ती चौक, शिकारपुर, पटना सिटी**

आक्षेप और स्पष्टीकरण

आपकी पत्रिका के अक्तूबर '८८ अंक में 'आईटीआर कं० मौत के कगार पर' शीर्षक से प्रकाशित लेख में मेरे विरुद्ध लगाये गये आरोपों में जो विसंगतियां तथा गलत तथ्य हैं, उनकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे अप्रैल १९८७ में प्रबंध निदेशक द्वारा चीफ इंजीनियर (मेंटीनेंस) का अतिरिक्त कार्यभार इसलिए सौंपा गया था, क्योंकि चीफ इंजीनियर का स्थानांतरण एल्कोहल परियोजना में कर दिया गया था। जो ढेर सारे पद लेख में लिखे गये हैं, वे मेरे पास नहीं हैं। नीलामी अधिकारी का कार्य मैं नहीं देख रहा हूं। यह कार्य प्रोडक्शन मैनेजर तथा अतिरिक्त लेखा अधिकारी देख रहे हैं। स्टोर परचेज आफीसर का कार्य मुझसे पहले वाले दो कारखाना प्रबंधकों द्वारा भी किया जा रहा था, इसमें से भी स्टोर का कार्यभार जून '८८ से प्रोडक्शन मैनेजर को सौंप दिया गया है। मै थर्मेक्स कं० से मात्र ब्वायलर खरीदने का सौदा तय किया गया था न कि एल्कोहल प्लांट लगाने का जैसा कि लेख में लिखा है।

मेरे बारे में व्यक्तिगत संपत्ति का जो विवरण दिया गया है, वह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है।—**केबी अग्रवाल, कारखाना प्रबंधक, द इंडियन टरपेंटाइन रोजिन कं०लि०, कलक्टर गंज, बरेली**

आप द्वारा १५ फरवरी, १९८९ की 'माया' में प्रकाशित लेख 'स्थानीय निकाय चुनाव: दलों को निर्दलों की शिकस्त' में उल्लेख है, ''धन, ताकत का खेल कानपुर के गोविंद नगर वार्ड से पंजाबी वर्ग के रहनुमा उद्योगपति देशराज के नाती अजय कपूर चुनाव लड़े और पैसे का खेल-खेला, तथा उनके समर्थन में स्व० विलायती राम कत्याल एमएलए की विधवा पत्नी ने घर-घर जाकर वोट मांगे।''

उपरोक्त तथ्य सत्य से परे है। इसके लेखक ने पाठकों को भ्रमित व गलत सूचना उपरोक्त संदर्भ में दिया है। मैंने ४३६५ वोट प्राप्त किये, जिसे मतदाता ने प्रथम वरीयता पर रखा। गोविंद नगर वार्ड नं० २९ मे मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तभी मुझे सभासद घोषित किया गया।

मैं मात्र पंजाबी वर्ग का रहनुमा नही हूं। मैं एक अदना सा सेवक बनाया गया हू, जिसमें यहां की जनता ने विश्वास प्रकट किया है। अतः यह कहना सर्वथा अन्याय व पक्षपात होगा कि मैं पंजाबी वर्ग का रहनुमा हूं।—**अजय कपूर, १२७ लाल क्वार्टर, गोविंद नगर, कानपुर**

◆ खयालात

अगरचे सलमान रुश्दी माफी मांग लें और हमेशा-हमेशा के लिए पाक इसान बन जायें, तो भी हर मुसलमान के लिए यह लाजिम है कि वह उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए अपना सबकुछ...अपनी जान, अपनी दौलत—कुर्बान कर दे।—**अयातुल्ला रुहोल्ला खोमैनी, तेहरान में।**

मौत का तीर छूट चुका है और मजहब की तौहीन करनेवाले दोगले-सलमान रुश्दी के सीने की तरफ जा रहा है।—**ईरानी राष्ट्रपति अली खोमैनी, तेहरान में।**

ऐसा फतवा वही जारी कर सकता है जो न किसी मजहब की परवाह करता है और न किसी मुल्क की, बल्कि खुद को सबका सरताज बनाये रखने के लिए लोगों में जंगली जुनून जगाता रहता है।—**ईरानी छात्र संगठन के महासचिव आर हसन, नयी दिल्ली में।**

अगर 'सेटेनिक वर्सेज' (रुश्दी की विवादास्पद पुस्तक) का जवाब देना ही था, तो वे (खोमैनी) 'एंजेलिक वर्सेज' लिख देते, इस्लाम को बदनाम करनेवाला फतवा क्यों दे डाला? **—माकपा सांसद सैफुद्दीन चौधरी, 'टेलीग्राफ' में।**

अगर हम हिटलर की बर्बरता के लिए उसकी निंदा कर सकते हैं, तो खोमैनी की (उनके फतवे के लिए) निंदा क्यों नहीं कर सकते?—**साहित्य अकादमी पुरस्कार पाये हिंदी के कवि नरेश मेहता, दिल्ली में।**

अयातुल्ला खोमैनी

राष्ट्रीय मोर्चा कुनबापरस्त और जातिवादी ताकतों की गोलबंदी है, ...भ्रष्ट तत्वों का गठबंधन है। वे (तत्व) कांग्रेस-इ को भ्रष्ट कहते हैं, लेकिन जब कोई भ्रष्ट आदमी हमारी पार्टी छोड़ कर उनसे जा मिलता है, तब वह पाक-साफ हो जाता है। **—राजीव गांधी, बजट सत्र की पूर्व संध्या पर, इंका संसदीय दल की बैठक में।**

राजीव गांधी की टिप्पणी भय से भ्रमित आदमी की भंड़ास मात्र है। राष्ट्रीय मोर्चे के उदय से प्रधानमंत्री की रात की नींत हराम हो गयी है। लगता है, वे संतुलन खो चुके हैं। **—विश्वनाथप्रताप सिंह, नयी दिल्ली में।**

लालकृष्ण आडवाणी

आप संसद के नही, प्रधानमंत्री के वेतन पर चल रहे हैं।—**केरल के जनता सांसद श्रीधरन (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रति) राज्यसभा में।**

राजीव गांधी के प्रति मेरी उतनी ही आस्था है, जितनी भगवान के प्रति। **—बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया, दिल्ली में।**

बंगाल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा के साथ चुनाव-करार के खतरनाक रास्ते पर चल रही है। **—भाकपा महासचिव सी राजेश्वर राव, पटना (भाकपा सम्मेलन) में।**

वे (भाकपावाले) बदनीयती के साथ हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ताकि राजीव गांधी को खुश कर सकें।—**मुख्यमंत्री ज्योति बसु, कलकत्ता ('जनशक्ति') में।**

राजनीति में मेरे जाने-न-जाने के बारे में इतनी माथापच्ची क्यों? बिहार और यूपी में तो बहू की राजनीति चलती ही है।—**नंदिनी आजाद (भागवत झा आजाद की पुत्रवधू), दिल्ली में।**

राजनीति की भरमार और खेल के नितांत अभाव से संसद एक नीरस निकाय बन कर रह जाती है, अतः अगले आम चुनाव में लोकसभा के पांच प्रतिशत टिकट खिलाड़ियों को दिये जाने चाहिए।—**मुख्य अधिशासी पार्षद जगप्रवेश चंद्र, दिल्ली में**

कांग्रेस जा रही है और अपने कुकृत्यों के कारण जा रही है—इस कारण नहीं कि विपक्षी दल कोई विशेष रुख अपना पाये हैं।—**भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, नवभारत टाइम्स में।**

विश्वनाथप्रताप सिंह 'बोफर्स' से मुक्ति पाकर 'लोफर्स' में फंस गये हैं।—**जद विधायक नवलकिशोर शाही (रघुनाथ झा के बिहार जद अध्यक्ष बनाये जाने पर), पटना में।**

फिल्मी सितारे भीड़ तो जुटा सकते हैं, पर उसमें लंबे समय तक जमे नहीं रह सकते और इसके बिना कोई राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता।—**देव आनंद, दिल्ली में।**

पहले के (संगीत) आयोजक कला और कलाकार को समझते थे, पर अब हाल यह है कि जिन्हें कला से कुछ भी लेना-देना नहीं, उनका आयोजनों पर एकाधिकार-सा हो गया है।—**नृत्यांगना राधिका राजपाल, 'जनसत्ता' में।**

डायमंड पाकेट बुक्स में

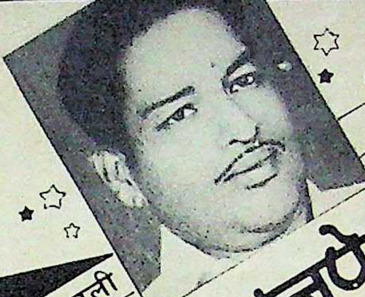

प्रतिभाशाली उपन्यासकार

प्रेम बाजपेयी का नया उपन्यास

भाई का इंसाफ

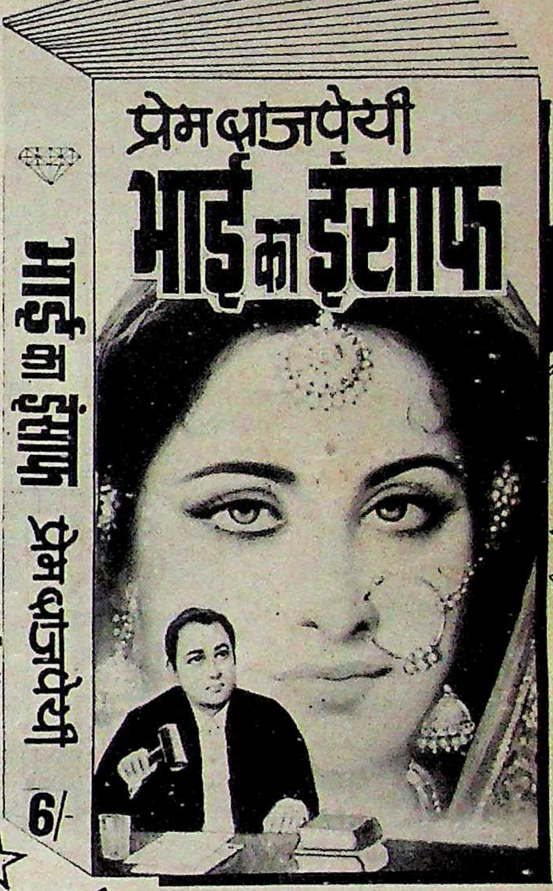
प्रेम बाजपेयी
भाई का इंसाफ
भाई का इंसाफ प्रेम बाजपेयी
6/-

लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार

विक्की आनन्द का नया जासूसी उपन्यास

कांपती आवाज़

विक्की आनन्द
कांपती आवाज़

समीर का नया उपन्यास

दौलत और ममता

समीर
दौलत और ममता
10/-

डायमंड पाकेट बुक्स प्रा. लि.
2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

लेकिन विपक्ष ने माफ नहीं किया

जब राजीव गांधी भारी बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीत कर आये थे, तो विपक्ष की स्थिति बहुत खराब थी। करीब दो साल तक समूचा विपक्ष मरा पड़ा रहा। लेकिन उसके बाद कई राज्यों में विपक्ष ने जब कांग्रेस को हराया, तो उसकी साख बनने लगी। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस की स्थिति में गुणात्मक गिरावट दिखायी पड़ी और दिल्ली में प्रचंड बहुमत के बावजूद उसके मनोबल में कमी आयी। पहले कांग्रेस 'पात-पात' थी और विपक्ष 'डाल-डाल' था। लेकिन जब वीपी सिंह कांग्रेस से बोफोर्स के मामले को लेकर अलग हुए, तो विपक्ष की पूरी फिजा ही बदल गयी। इलाहाबाद चुनाव के बाद तो पासा बिलकुल पलट गया। विपक्ष 'पात-पात' और कांग्रेस 'डाल-डाल' हो गयी।

अभी पिछले दिनों २७ फरवरी को संसद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विपक्ष पर 'खालिस्तानी' कह कर बहुत कड़ी चोट कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पूरा विपक्ष आतंकवाद को अपना समर्थन दे रहा है। इस पर पूरा विपक्ष नाराज होकर सदन से बाहर चला गया। दूसरे दिन लोकसभा में बजट पेश होना था। विपक्ष ने शर्त रखी कि जब तक राजीव गांधी माफी नहीं मांगते, तब तक वे लोग सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। २८ फरवरी की सुबह राज्यसभा में राजीव गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जब वे अपने कार्यालय गये, तो एचकेएल भगत, बूटा सिंह आदि ने उनको यह समझाया कि अगर वे माफी मांग लें, तो विपक्ष संसद में लौट आयेगा। बजट के समय विपक्ष के सदन में न रहने से उनकी प्रतिष्ठा को काफी बड़ा धक्का लगेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक लम्बे समय के बाद आये आरके धवन ने भी राजीव गांधी को यह समझाया कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए। वित्त मंत्रालय में गये गोपी अरोड़ा भी इसी राय के थे। जब सभी ओर से दबाव पड़ा, तो राजीव गांधी माफी मांगने के लिए तैयार हो गये। लेकिन उन्होंने पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि माफी मांग लेने के बाद विपक्ष संसद में वापस लौट आयेगा? इस पर गृहमंत्री बूटा सिंह ने बताया कि उनको इस तरह की गुप्तचरों (आईबी) से सूचना मिली है कि अगर माफी मांग ली गयी, तो विपक्ष अपना बहिष्कार वापस लेकर संसद में आ जायेगा। भगतजी ने भी कहा कि उनकी कई विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत हुई है। उनका कहना था कि अगर प्रधानमंत्री परोक्ष रूप से भी खेद प्रकट कर दें, तो वे लोग वापस आ जायेंगे। इस पर राजीव गांधी ने संसद में अपने कहे पर खेद प्रकाश कर दिया। लेकिन विपक्ष इसके बावजूद नहीं आया।

जानकार सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के नेताओं ने जान-बूझकर ऐसा भ्रम पैदा किया था कि अगर राजीव गांधी माफी मांग लें, तो वे लोग संसद में वापस लौट आयेंगे। लेकिन वे लोग पहले ही मन बना चुके थे कि बजट का बहिष्कार किया जायेगा। जब विपक्ष बजट के समय वापस नहीं आया, तो राजीव गांधी ने भगत, बूटा सिंह आदि को कसकर फटकार लगायी और आईबी को काफी कसा कि वह यह सूचना कैसे लाया कि माफी मांग लेने के बाद विपक्ष वापस आ जायेगा? लेकिन राजीव गांधी को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अगर कांग्रेस 'डाल-डाल' है, तो विपक्ष अपनी रणनीति में 'पात-पात' है।

जब पहाड़िया के दिन बहुरे

बिहार के नये राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने पिछले दिनों दिल्ली के बीकानेर हाउस में पटना जाने के पहले पत्रकारों को बीकानेर की प्रसिद्ध मिठाई खिलायी और बताया कि वे राजनीति में किस तरह आये।

पहाड़िया ने बताया कि एमए करने के बाद वे नौकरी की तलाश में अपने एक रिश्तेदार से दिल्ली में मिलने आये। उनका रिश्तेदार प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के तीनमूर्ति में माली था। वे उसी के तीनमूर्ति के क्वार्टर में आकर ठहरे। उनके माली रिश्तेदार ने पहाड़िया से कहा कि वे सुबह नेहरूजी को एक गुलाब का फूल देकर उनके दर्शन कर आयें। पहाड़िया जब गुलाब का फूल लेकर नेहरूजी के पास पहुंचे, तो नेहरूजी ने पूछा कि तुम क्या करते हो? पहाड़िया ने जवाब दिया कि नौकरी की तलाश में हूं। नेहरूजी ने कुछ नहीं कहा। शाम को लाल बहादुर शास्त्रीजी के यहां उन्हें बुलाया गया।

शास्त्रीजी ने पहाड़िया से कहा कि नेहरूजी की इच्छा है कि तुम हरिजनों के बीच काम करो। पहले पहाड़िया ने आनाकानी की। लेकिन शास्त्रीजी ने समझाया कि जब नेहरूजी ने तुमको कोई काम करने के लिए दिया है, तो इसमें तुम्हारी भलाई ही होगी। पहाड़िया ने राजस्थान जाकर राजनीतिक काम शुरू कर दिया। फिर क्या था? नेहरूजी की कृपा से उनको विधानसभा का टिकट मिला और वे आगे बढ़ते गये। पिछले दिनों पहाड़िया राजनीतिक दृष्टि से बहुत उपेक्षित हो गये थे। उन्होंने राजीव गांधी से समय लेकर उनको अपनी कहानी सुनायी, तो उनके दिन बहुर गये। वे कुछ ही दिनों में कांग्रेस के महामंत्री बना दिये गये। क्या राज्यपाल के पद पर जाने के पीछे मुख्य प्रेरणा-स्रोत वही नेहरूजी के समय की कहानी है?

अजीत सिंह की हेठी

उप्र जनता दल के अध्यक्ष के रूप में मुलायम सिंह यादव के मनोनयन से अब अजीत सिंह गुट में गहरे मतभेद पैदा हो गये हैं। अजीत सिंह से सबसे ज्यादा नाराज हैं रामनरेश यादव। पिछले दिनों अजीत सिंह ने हरिकेश बहादुर को रामनरेश के पास समझाने-बुझाने के लिए भेजा था। लेकिन रामनरेश का गुस्सा अभी पूर्ववत बना हुआ है।

अजीत सिंह ने रामनरेश को झांसा दे रखा था कि वे उनको उप्र जनता दल का अध्यक्ष बनवा कर ही दम लेंगे। जब दिल्ली में जनता दल के संसदीय बोर्ड को उप्र के अध्यक्ष पद का फैसला लेना था, तो उसके पहले अजीत सिंह, रामनरेश यादव को लेकर चंद्रशेखर के यहां गये और कहा कि यादव को उप्र जनता दल का अध्यक्ष बनवा दीजिए। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, "अभी पिछले दिनों तो तुम मेरे पास रशीद मसूद को अध्यक्ष बनाने के लिए लाये थे। आज रामनरेश को लेकर आये हो।" इस पर अजीत सिंह बहुत बुरी तरह खिसिया गये।

मुलायम सिंह की नियुक्ति से अजीत सिंह गुट ही नहीं, बल्कि संजय सिंह भी बहुत दुखी हैं। पिछले दिनों संजय सिंह भोंडसी आश्रम में चंद्रशेखर से मिलने गये थे। चंद्रशेखर का कहना था, "मुलायम सिंह को अध्यक्ष बनाना उनकी मजबूरी थी। जब मुलायम सिंह का बहुगुणा की तरफ झुकाव बढ़ रहा था, तो उनको इसी शर्त पर देवीलाल की तरफ लाया गया था कि उनको उप्र जनता दल का अध्यक्ष बना दिया जायेगा। इस बार वीपी सिंह ने भी अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की थी। वीपी सिंह तो कोई वायदा करके मुकर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं है। इसीलिए मैंने मुलायम सिंह को पूरा समर्थन दिया। ■

आपका भरोसेमंद फ़ैरेक्स, अब 'स्वाद में सबसे आगे'!

जब आपका शिशु ४ महीने का हो जाए,
उसे नया स्वादिष्ट फ़ैरेक्स देना शुरू कीजिए.
शुरू में एक छोटे चम्मच फ़ैरेक्स को ३-४ छोटे चम्मच
गुनगुने पानी में मिलाकर दीजिए. फ़ैरेक्स अब पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट,
मलाईदार और पौष्टिक है.

Delicious
Farex®
CEREAL WITH MILK
4 months
9 months
Give Farex Cereal with Milk with dal, kanji, suji or puddings.
12 months onwards
Add Farex Cereal with Milk to baby's daily diet and watch your baby grow.

- ज़्यादा मलाईदार
- ज़्यादा पौष्टिक

फ़ैरेक्स® - स्वाद भी पाए, बढ़ता भी जाए... मुन्ना.

GX/63/244 HIN

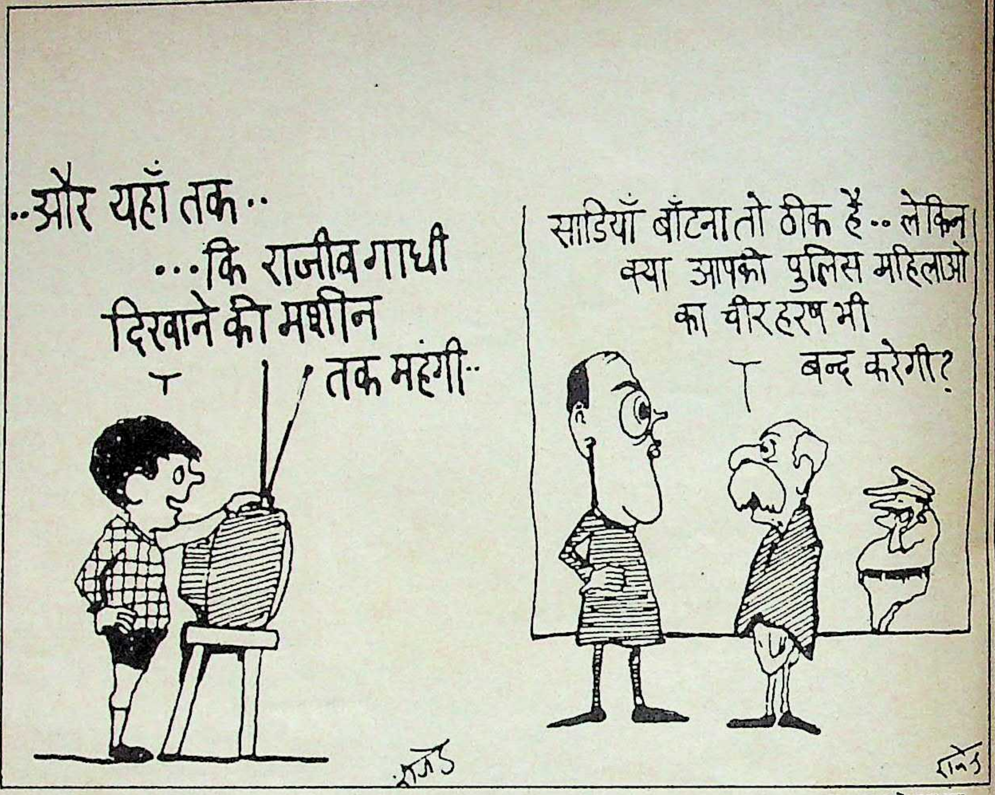
..और यहाँ तक..
...कि राजीव गाधी दिखाने की मशीन तक महंगी..
साडियाँ बाँटना तो ठीक है.. लेकिन क्या आपकी पुलिस महिलाओ का चीरहरण भी बन्द करेगी?

जनसत्ता से साभार

हे शंकर तांडव मत करना !

वित्त मत्रालय के नार्थ ब्लाक में हैड मास्टर (शंकर राव चह्वाण) का 'बजटी मेकअप' चल रहा था। वित्त सचिव वेंकिटरमणन अपने चश्मे का फोकस हैड मास्टर के भावरहित चेहरे पर फिक्स किये हुए डा० नितिन देसाई (मुख्य आर्थिक सलाहकार) को निर्देश दे रहे थे, ''मंत्रीजी के चेहरे पर घाटे का पाउडर बहुत गहरा हो गया है। उसे थोड़ा हल्का करो। माथे पर 'कंप्यूटरी बिंदिया' लगाओ। एक हाथ में ट्रांज़िस्टर दो। देख लेना टू इन वन हो।'' पास खड़े (खर्च सचिव) आरआर गुप्ता ने वेंकिटरमणन के कान में कहा ''वेंकिट, मंत्रीजी पानं मसाला बहुत जरूर है।'' उसको थुकवा कर मुंह में सिगरेट लगवाओ। चेहरे पर रौब उभारना बहुत जरूरी है।'' वेंकिटरमणन ने गौर से मंत्रीजी का चेहरा देखा, ''गुप्ता, मैं सोचता हूं कि पान मसाला न उगलवाया जाये। उसी के ऊपर सिगरेट लगवा दी जाये।'' वेंकिटरमणन ने निर्देश देने के बाद सुस्ताने के लिए सिगरेट सुलगा कर गहरा कश खींचकर मंत्रीजी के चेहरे पर चल रही बजटी पुताई की ओर निहारा, ''देखो गुप्ता, मंत्रीजी २८ फरवरी को नार्थ ब्लाक के संसद भवन के गेट तक स्कूटर पर चढ़कर जायेंगे। उसके बाद कार में उनको बिठाकर ले जाया जायेगा। विपक्ष से सुरक्षा के लिए उनको इस्पात की एक ढाल और प्रहार करने के लिए लोहे की तलवार देना मत भूलना। मैं अपनी जिंदगी का यह लास्ट (आखिरी) बजट मेकअप करा रहा हूं। किसी तरह की कोई कमी न रह जाये।''

वेंकिटरमणन ने सिगरेट का गहरा कशं खींचते हुए मेकअप रूम से बाहर अपने कक्ष में जाने के लिए कदम बढ़ाये, तो पीछे से गढ़वी, फलेरियो, पांजा ने उनको घेर लिया, ''सर, चह्वाण साहब का तो बहुत अच्छा मेकअप हो रहा है। हम लोगों के चेहरों पर भी कुछ लाल-पीला चूना पुतवा दीजिये। होली आने वाली है...।' वेंकिटरमणन ने हल्का सा मुस्करा कर कहा, ''बजटी मेकअप के लिए आप लोगो का कोई हक नहीं बनता है। मैं संविधान के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? हां, चुनाव तो आने वाले हैं, उसमें जनता आप का अच्छा खासा मेकअप कर देगी। थोड़ा इंतजार कीजिये।'' तीनों बहुत मायूस हो उठे। वेंकिटरमणन मेकअप रूम से बाहर निकलने को ही थे कि सामने से दनदनाते हुए गोपी अरोड़ा आ गये, ''वेंकिटी, मंत्रीजी का क्या बजटी मेकअप हो रहा है? जरा देखना चाहता हूं।'' वेंकिटरमणन ने मेकअप रूम की चौखट पर हाथ रखकर उसे छेक लिया, ''गोपी, अभी मैं वित्त सचिव हूं। मंत्रीजी का क्या मेकअप होगा, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। तुम मंत्रीजी का मेकअप देख सकते हो, लेकिन उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हो।'' गोपी अरोड़ा ने वेंकिटरमणन को धकिया दिया, ''वेंकिटी, अब दिल्ली दरबार में 'साउथ लाबी' के दिन लद गये। मैं 'नार्थ ब्लांक' में लाकर इसीलिए बिठाया गया हूं कि 'नार्थ लाबी' को यहां भी प्रतिष्ठित करूं।'' वेंकिटरमणन को पसीना आ गया, ''यह क्या! साउथ ब्लाक में साउथ लाबी तो लंबे अर्से से खदेड़ी जा चुकी है। अब नार्थ ब्लाक में भी साउथ लाबी भगा दी जायेगी?'' गोपी ने दांत पीसते हुए कहा, ''अब तुम साउथ लाबी के लोग किस मुंह से दिल्ली दरबार में रह पाओगे। सारा साउथ (केरल, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु) तो विरोधी दलों के हवाले करा दिया। अब तुम साउथ लाबी के पास कोई नैतिक आधार नार्थ और साउथ ब्लाक में बने रहने का नहीं रह गया है। इसीलिए मुझे दिल्ली दरबार ने नार्थ ब्लाक में तुम्हारी जगह तैनात किया है।'' जब नार्थ ब्लाक में ही बैठने वाले पी चिदंबरम के कान में गोपी अरोड़ा की गर्जना पड़ी, तो वे अपनी लुंगी संभालते हुए आ पहुंचे, ''अरे, गोपी भाई। मुल्क में काफी फसाद यों ही चल रहा है। अब तुम अफसरों की नार्थ और साउथ लाबी इस तरह टकरायेगी, तो दिल्ली दरबार की चूल-चूल हिल जायेगी।'' गोपी अरोड़ा ने चिदंबरम को झिड़कते हुए कहा, ''सर, तमिलनाडु चुनाव की हार के बाद आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है दिल्ली दरबार ने आप पर रहम करके उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन

आपके पास भी कोई नैतिक अधिकार साउथ लाबी को बचाने के लिए नहीं बचा है। आप अगर कुछ और दिनों नार्थ ब्लाक में रहना चाहते है, तो मेरे बीच में न आयें।" चिदंबरम ने गोपी अरोड़ा को अपनी आक्सफोर्डी अंग्रेजी में समझाना शुरू किया, तो वे विशुद्ध इलाहाबादी में उतर आये, "सर, अब आप अपनी खैर मनायें। मुझे समझाने के दिन अब आपके लद गये हैं।" गोपी अरोड़ा आगे बढ़ गये, तो चिदंबरम ने अपनी मुंडिया वेंकिटरमणन के कंधे पर टिका कर विशुद्ध तमिल में रोना शुरू कर दिया। जवाब में वेंकिटरमणन भी विशुद्ध तमिल में सुबकने लगे।

गोपी अरोड़ा ने मेकअप रूम में पहुंच कर नितिन देसाई के हाथ से कूची छीन ली, "देसाई, मंत्रीजी का बजट मेकअप बदलना होगा। यह साउथ लाबी बहुत शैतान है। पिछले चार 'बजट मेकअप' इसने ऐसे कर दिये कि दरबार का कबाड़ा निकाल दिया। इस बार हम लोगों को मंत्रीजी का 'चुनावी मेकअप' करना होगा। उतारो, इस साली 'कंप्यूटरी बिंदिया' को मंत्रीजी के माथे पर से और लगा दो इस पर कुछ और टैक्स।" देसाई ने घबरा कर कहा, "गोपीजी दरबार की सबसे प्रिय चीज (कंप्यूटर) पर अगर टैक्स बढ़ा दिया, तो वे आपे से बाहर हो जायेंगे। पहले दरबार से पूछ लिया जाये!" गोपी अरोड़ा ने देसाई को झिड़क दिया, "नितिन, दरबार की सुनोगे, तो वे हम लोगों को भी कंप्यूटरो से बदलने की बात कहेंगे। मुल्क में 'नौकरशाही लोकतंत्र' है। नौकरशाह जो कहेगा, अंत में वही होगा। मैं दरबार का नौकरशाह शिरोमणि हूं। मैं जो कहता हूं, वही करो। जो मैं कहता हूं वही दरबार कहेंगे, क्योंकि देश में 'नौकरशाही लोकतंत्र' की जड़ें बहुत मजबूत हैं।" डा० नितिन देसाई ने गदगद होकर गोपी अरोड़ा की हां में हां मिलाने के लिए गर्दन हिला दी।

गोपी अरोड़ा गरजे, "मंत्रीजी के चेहरे पर 'रोजगार दिलाओ, गरीबी हटाओ' का गहरा लाल रंग मलो। इससे घाटे का मटमैला रंग अपने आप दब जायेगा। मंत्रीजी का मुंह फिनाइल डालकर साफ कराओ, ताकि पान मसाला दूर-दूर तक उसमें न रह पाये। सिगरेट मुंह से निकाल कर पान मसाले की तरह उस पर भी टैक्स बढ़ा दो। अरे, हाथ में यह टू इन वन क्यों थमा रखा है? इसको भी दूर फेंको। बढ़ा दो इस पर भी टेलीविजन के साथ कर।" डा० नितिन देसाई अपने दलबल के साथ हैड मास्टर साहब के चेहरे पर गोपी अरोड़ा के निर्देशन में पिल गये। जैसे ही 'रोजगार दिलाओ, गरीबी हटाओ' का चटकीला लाल रंग मंत्रीजी के चेहरे पर मला गया, वे वेताल पच्चीसी के दैत्य की तरह 'ही...ही' करने लगे। देसाई घबरा गये। लेकिन सिगरेट का कश ले रहे गोपी अरोड़ा ने मुस्करा कर धीरे से कहा, "काफी लंबे अर्से बाद वित्त मंत्री के चेहरे पर गरीबी हटाओ का मेकअप मला जा रहा है, इसलिए दैत्य हंसी बहुत स्वाभाविक है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाथ में माचिस दो और मंत्रीजी से कहो कि गरीब का चूल्हा जलायें।" देसाई ने थोड़ी देर के बाद मेकअप करते-करते फिर घूमकर गोपी अरोड़ा की तरफ देखा, "सर, यह बजटी मेकअप काफी वीभत्स होता जा रहा है। मंत्रीजी हू...हू करके उछल रहे हैं।" गोपी अरोड़ा ने संयत स्वर में अपने लंबे बालों को ठीक करते हुए कहा, "कुछ नहीं, मुझे रोजगार दिलाओ और गरीबी हटाओ के लिए वीभत्स मेकअप ही चाहिएं। चुनावी साल है, अगर इस साल भी वित्त मंत्री ने गरीबी हटाओ और रोजगार दिलाओ का तांडव नहीं किया, तो सब चौपट हो जायेगा।"

नार्थ ब्लाक में वित्त मंत्री का बजटी मेकअप चल ही रहा था कि संसद भवन से आरके धवन भागे-भागे आये, "अरे, गोपी भाई आप यहां चह्वाण साहब के गरीबी हटाओ, रोजगार दिलाओ के तांडवी मेकअप में जुटे हुए हैं और उधर दरबार को उस मद्रासी चिदंबरम ने भड़का कर 'तांडव' करा दिया। सारा विपक्ष संसद से बहिर्गमन कर गया है। अब विपक्ष ने घोषणा कर दी है कि वह वित्तमंत्री चह्वाण का कल (२८ फरवरी) बजट तांडव नृत्य नहीं देखेगा। विपक्ष कह रहा है कि दरबार माफी मांगे।" गोपी अरोड़ा झटका खा गये, "इस चिदंबरम के बच्चे ने अपना मद्रासीपन दिखा ही दिया। अब क्या होगा! जंगल में मोर नाचेगा, तो कौन देखेगा। दरबार से कहो कि विपक्ष से माफी मांग ले। अपने वित्तमंत्री का अगर नृत्य विपक्ष को नहीं दिखाया, तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जायेगा।" धवन यह कहकर उल्टे पांव लौट गये, "अच्छा, मैं दरबार को समझाने की कोशिश करता हूं कि वे विपक्ष से माफी मांग कर उसे कल कम-से-कम वित्तमंत्री का गरीबी हटाओ तांडव तो दिखा दें।" वित्त सचिव वेंकिटरमणन ने अपने कक्ष के दरवाजे से झांक कर देखा और अंदर ही अंदर बहुत खुश होकर तुरंत पी चिदंबरम को फोन मिलाकर विशुद्ध तमिल में बधाई दी, "तुमने इन नार्थ लाबी को अच्छा छठी का दूध याद दिला दिया। लगे रहो। कल अगर संसद में विपक्ष न आया, तो गोपी अरोड़ा का सारा खेल धरा का धरा रह जायेगा।" चिदंबरम ने वेंकिटरमणन को फोन काट देने के लिए कहा, "अरे तू तो रिटायर्ड हो रहा है। क्या मेरी नौकरी भी खा जायेगा? मोहन कात्रे (सीबीआई, प्रमुख) का कार्यकाल इसीलिए बढ़ाया गया है कि वे हम सब पर नजर रखें।" वेंकिटरमणन ने तुरंत फोन काट दिया।

> **इस स्वर में उस समय जान आ गयी जब बालकवि वैरागी दाढ़ी खुजलाते हुए दरबार में आ गये, "हुजूर, मैं कवि हूं। हर भाव और वजन पर आशुकविता करता हूं। अगर आप लोग वित्तमंत्री चह्वाण के तांडव के खिलाफ हैं, तो मैं कल यह कविता पढ़ दूंगा—**
>
> **"बगिया की रंगत बनी रहे, फूलों को तंग मत करना। माली का रुतबा बना रहे। हे शंकर, तांडव मत करना।" दरबारी कविता से झूम उठे—"ठीक है, ठीक है। हे शंकर, तांडव मत करना।"**

दरबार में सन्नाटा था। धवन पूरी स्थिति साफ कर चुके थे। दरबार विपक्ष से माफी मांग चुका था। एचकेएल भगत ने सिर झुका कर दरबार को सूचित कर दिया था कि 'माफी मांगने के बावजूद विपक्ष कल बजट में शामिल नहीं हो रहा है।' शीला दीक्षित मंद-मंद मुस्करा रही थीं कि "मेरे पर काटने के लिए अब धवन को लाया गया है। कर पाये कुछ धवन? मैं तो अब विपक्ष को फुसलाने से रही!" खामोशी को चिदंबरम ने आहिस्ता से यह कह कर तोड़ा, "तांडव का अधिकार तो मात्र दरबार को है। अगर कोई वित्तमंत्री चह्वाण से रोजगार दिलाओ, गरीबी हटाओ का तांडव करने की फिराक में है, तो मैं उसका विरोध करता हूं।" धीरे-धीरे दरबार में और स्वर फूटने लगे, "हां, हां जब दरबार मौजूद हैं, तो उन्हें ही तांडव का अधिकार है। दरबार के रहते कोई और तांडव कैसे कर सकता है?" इस स्वर में उस समय जान आ गयी जब बालकवि वैरागी अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए दरबार में आ गये, "हुजूर, मैं कवि वैरागी हूं। हर भाव और वजन पर आशुकविता करता हूं। अगर आप लोग वित्तमंत्री शंकर राव चह्वाण के तांडव के खिलाफ हैं, तो मैं कल यह कविता पढ़ दूंगा—

"बगिया की रंगत बनी रहे, फूलों को तंग मत करना। माली का रुतबा बना रहे। हे शंकर, तांडव मत करना।" दरबारी कविता से झूम उठे—"ठीक है, ठीक है। हे शंकर, तांडव मत करना।"

—दरबारी लाल

घमौरियों से आराम के लिए टाल्कम पाउडर नहीं, नायसिल चाहिए.

नायसिल लगाइए. घमौरियों से जल्द आराम पाइए.

नायसिल एक **औषधियुक्त** पाउडर है. घमौरियों की हर परेशानी से फ़ौरन आराम दिलाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया. खुजली, जलन और चुनचुनाहट से तुरंत आराम दिलाता है और घमौरियों को फैलने व बढ़ने से रोकता है, जो टाल्कम पाउडर से संभव नहीं.

नायसिल–घमौरियों से आराम पाने का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद उपाय.

1. अत्यधिक पसीने को रोकता है.
2. पसीने को सोखता है.
3. बदबू पैदा करनेवाले कीटाणुओं का नाश करता है.
4. त्वचा को आराम पहुँचाता है.

To open, twist and pull cap
nycil
PRICKLY HEAT POWDER
200 GRAMS NET

HTA 1961

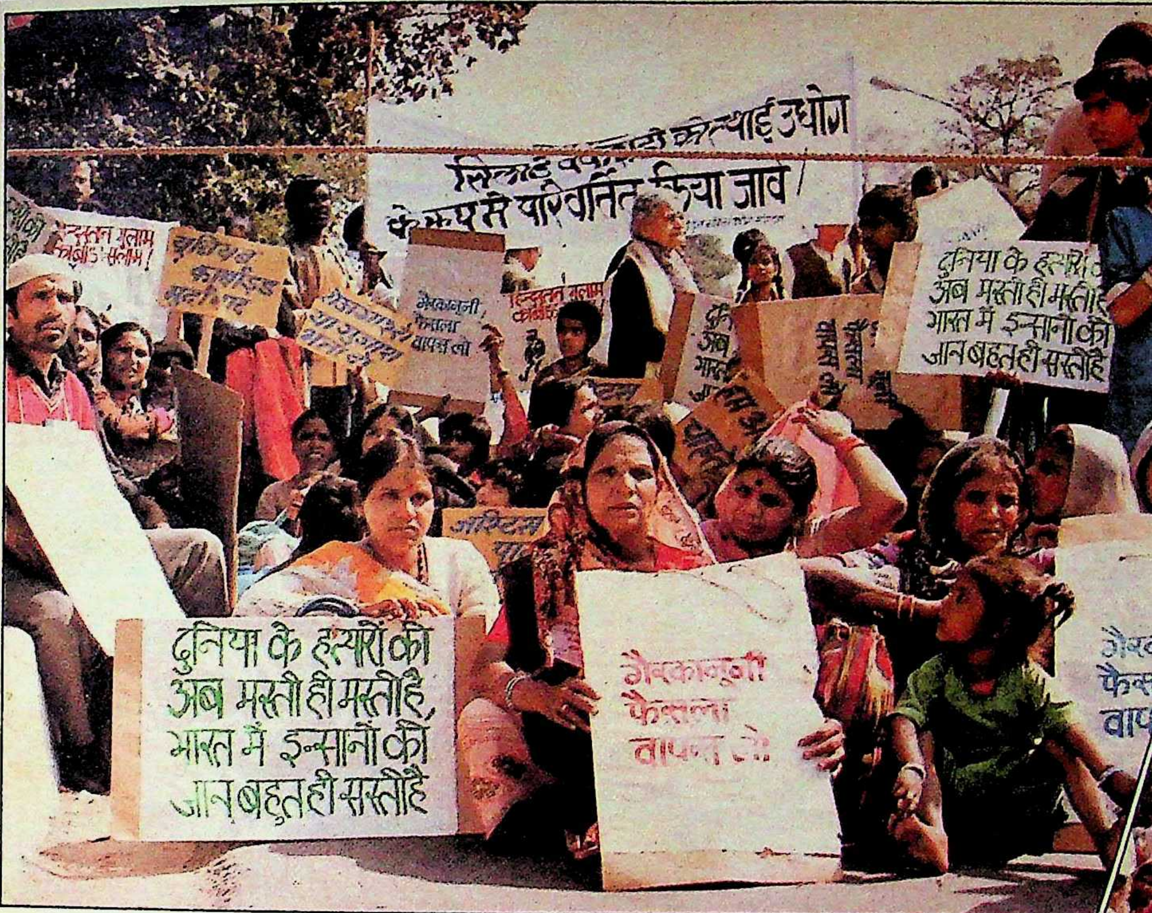
कल्याई उद्योग
के रूप से परिवर्तित किया जावे
हिन्दुस्तान गुलाम कार्बाइड सलाम!
गैरकानूनी फैसला वापस लो
दुनिया के हत्यारों की अब मस्ती ही मस्ती है, भारत में इन्सानों की जान बहुत ही सस्ती है
दुनिया के हत्यारों की अब मस्ती ही मस्ती है, भारत में इन्सानों की जान बहुत ही सस्ती है
गैरकानूनी फैसला वापस लो

१४ फरवरी को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आरएस पाठक की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय खंडपीठ ने १९८४ की भोपाल गैस त्रासदी के मुआवजे के रूप में यूनियन कार्बाइड को ४७ करोड़ डालर (७१५ करोड़ रुपए) अदा करने के निर्देश दिये। न्यायालय के इस फैसले से निराश होकर गैस पीड़ित फैसले का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुंचे। २१ फरवरी को लगभग २००० गैस पीड़ित महिलाओं और बच्चों ने उच्चतम न्यायालय के सामने प्रदर्शन किया और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ईएस वेंकटरमैया ने पिछले माह दिये गये फैसले से अपने को अलग रखने की इच्छा तक जाहिर कर दी।

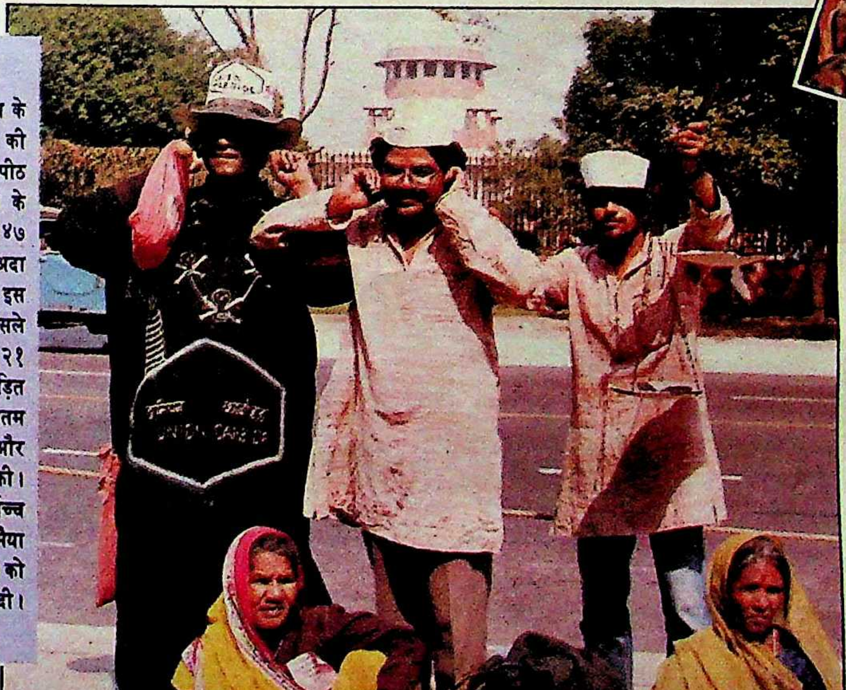
यूनियन कार्बाइड
UNION CARBIDE

छाया :
गिरीश श्रीवास्तव

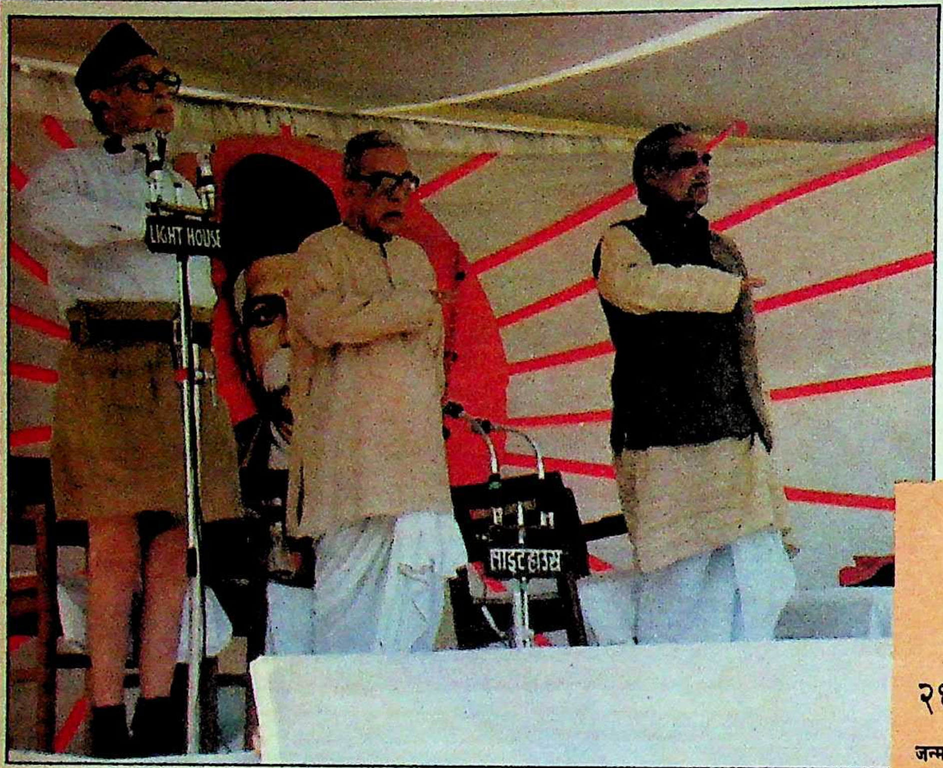

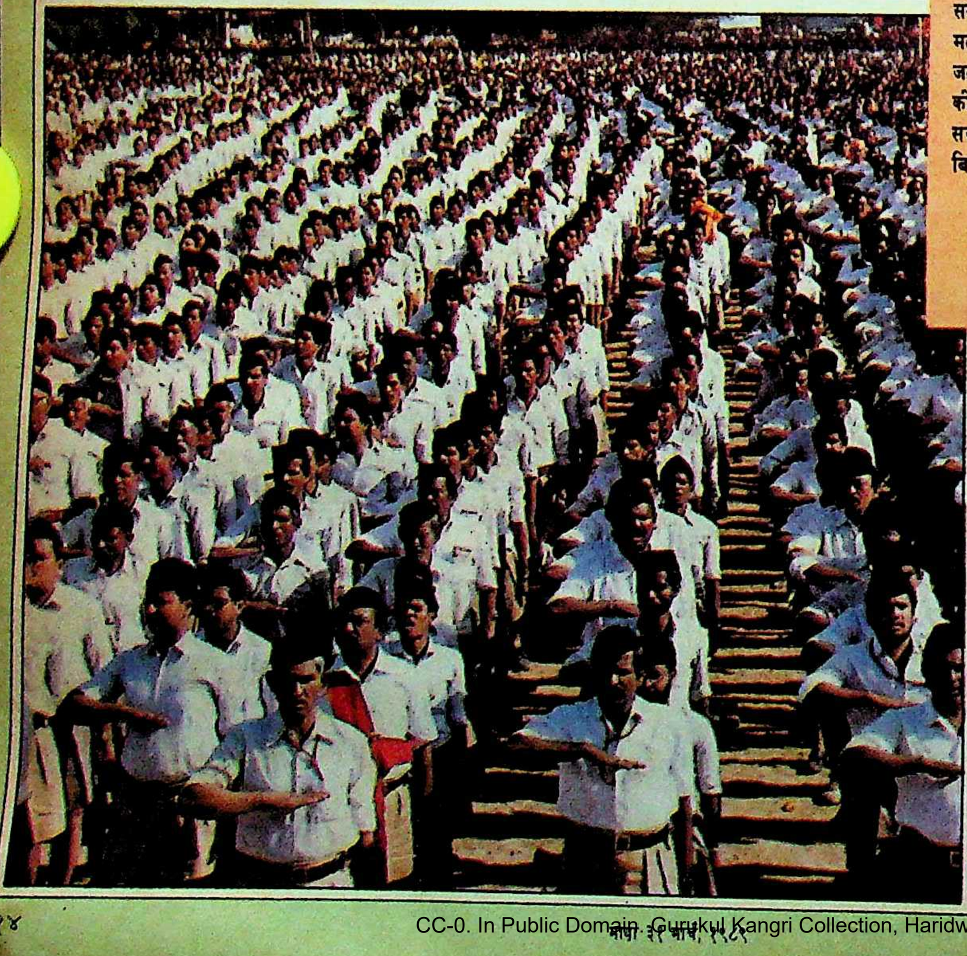

२६ फरवरी को लखनऊ में 'विराट हिंदू संगम' का आयो
हुआ। वैसे तो यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
जन्मदाता डा० केशव बलिराम हेडगेवार की जन्म शता
समारोह की एक कड़ी के रूप में था, पर इसका असली उद्देश्य
मतों को अपने हक में करना और भाजपा में अपना दुबारा विश
जताना था। यह पहला अवसर था, जब पचास हजार स्वयंसे
की उपस्थिति में एक मंच पर कांचि कामकोटि के शंकराचार्य ज
सरस्वती, सर संघ चालक बालासाहब देवरस के साथ अ
बिहारी वाजपेयी मिले और एक दूसरे का समर्थन किया।

छाया : राजेंद्र कुमार

का आयोज
सेवक संघ
जन्म शता
नी उद्देश्य
बारा विश
र स्वयंसेव
कराचार्य ज
साथ अ
किया।

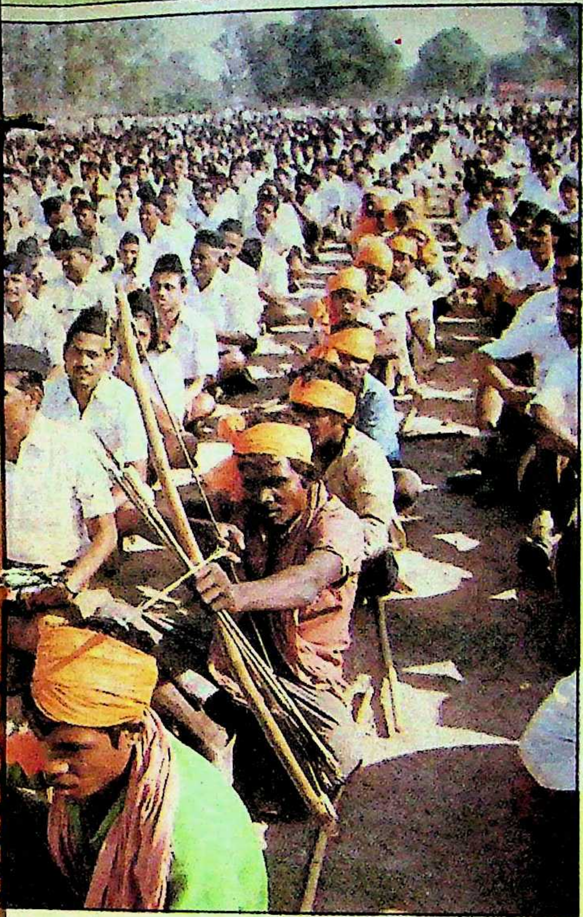

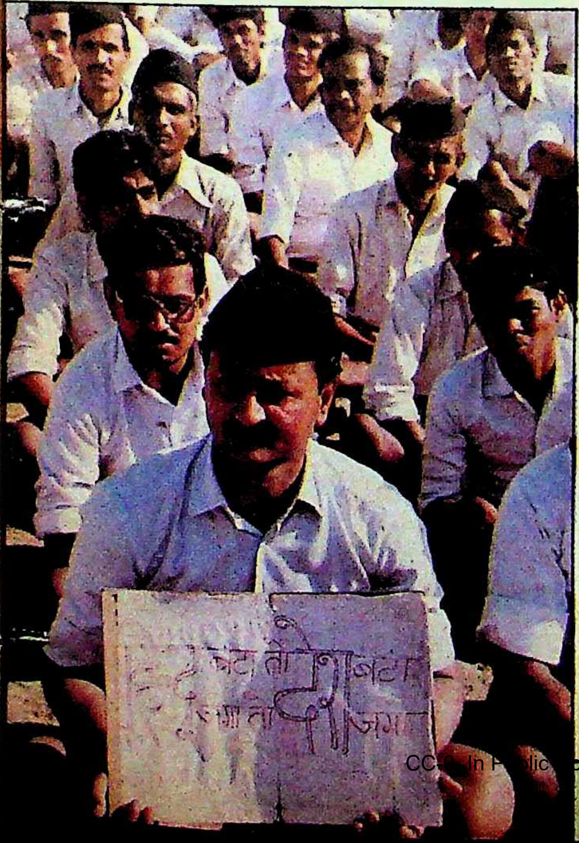

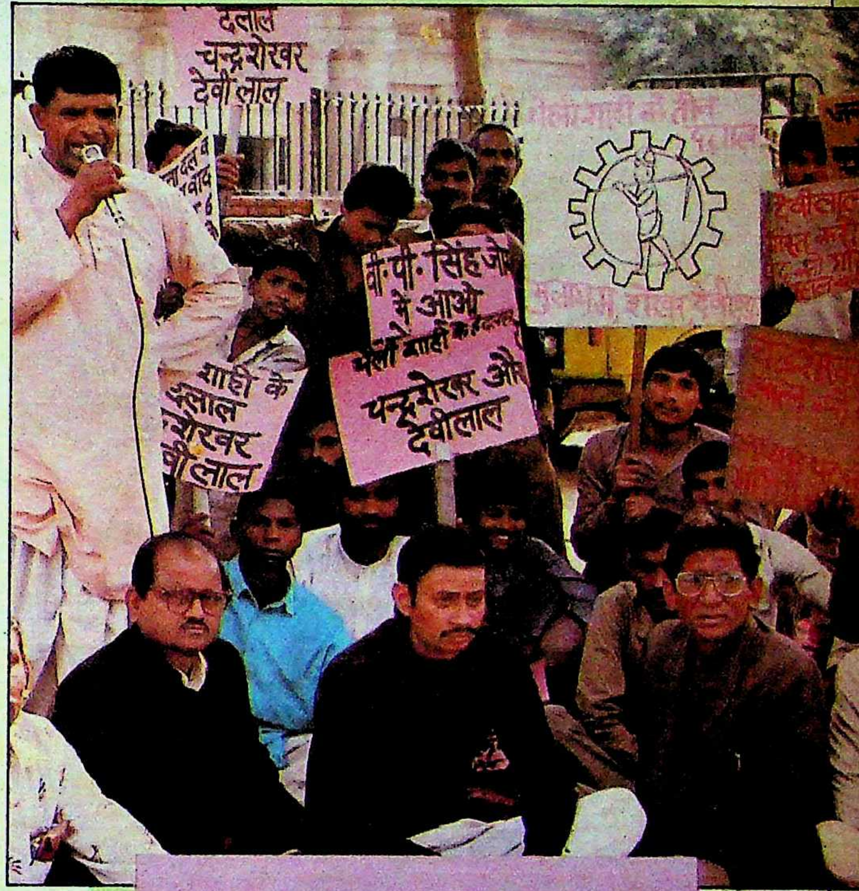
दलाल
चन्द्रशेखर
देवीलाल
वी.पी. सिंह जो
में आओ
शाही के दलाल
चन्द्रशेखर और
देवीलाल
शाही के
दलाल
चन्द्रशेखर
देवीलाल

हाल में जनता दल के प्रादेशिक अध्यक्षों के चयन के समय दिग्गज नेताओं द्वारा जिस ढंग से समीकरण बिठाये गये और उनके जो परिणाम सामने आये, उनसे जनता दल की असली तस्वीर सामने आ गयी। विशेषकर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिह यादव के चयन को लेकर तो ऐसा असंतोष पैदा हुआ कि लोकदल-अ घटक के पांच बड़े नेताओं ने इस्तीफे दे दिये। इसी क्रम में अपना असंतोष जाहिर करने तथा शीर्ष नेताओं के फैसले का विरोध करने के लिए 'जद' कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों 'जद' के दिल्ली स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया।

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

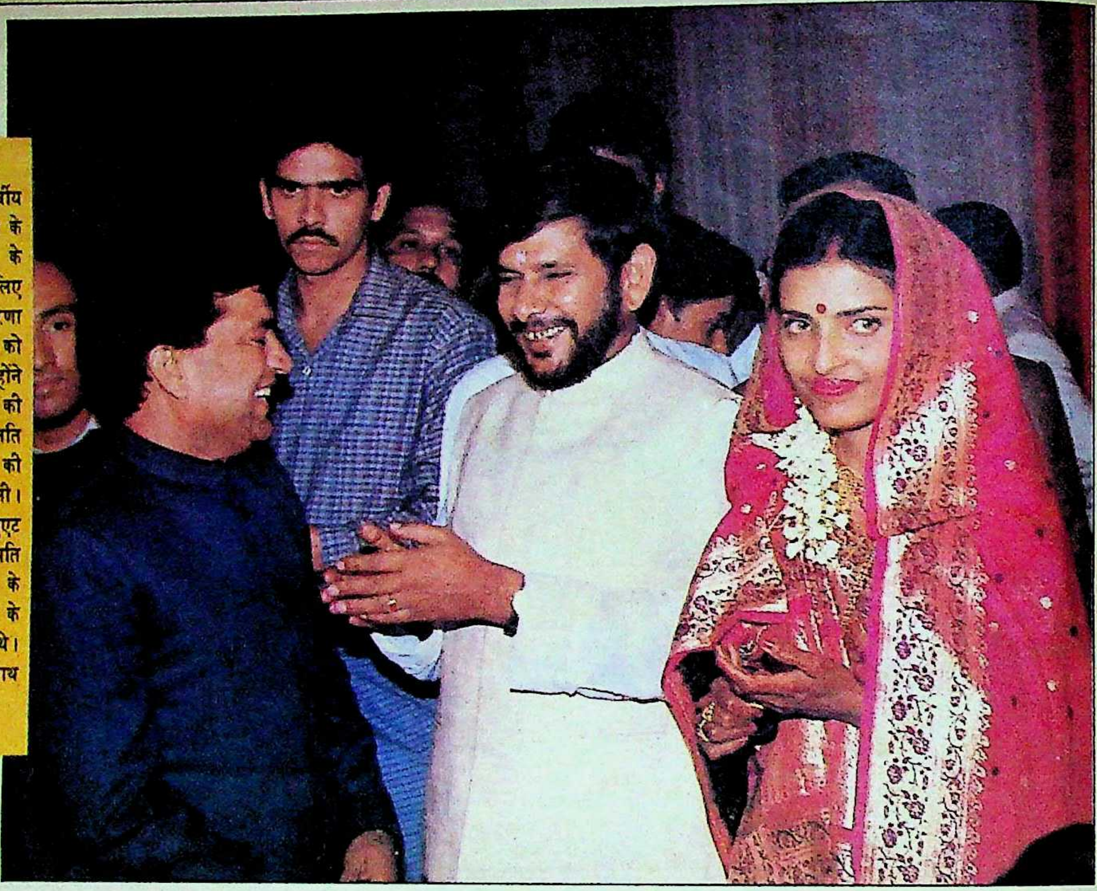

जनता दल के ४३ वर्षीय महासचिव और देवीलाल के उग्र अनुयायी शरद यादव के औघड़ जीवन में विवाह के लिए कोई जगह नहीं है—इस धारणा को शरद यादव ने १५ फरवरी को उस समय तोड़ दिया, जब उन्होंने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनति मेहता की अदालत में रिवाड़ी की डा० रेखा यादव से शादी कर ली। शरद यादव इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और रेखा यादव वनस्पति विज्ञान में पीएचडी। शादी के मौके पर सत्ता और विपक्ष के राजनेता और दोस्त मौजूद थे। इस अवसर पर वर-वधू के साथ राजेश पायलट।

छाया :
गिरीश श्रीवास्तव

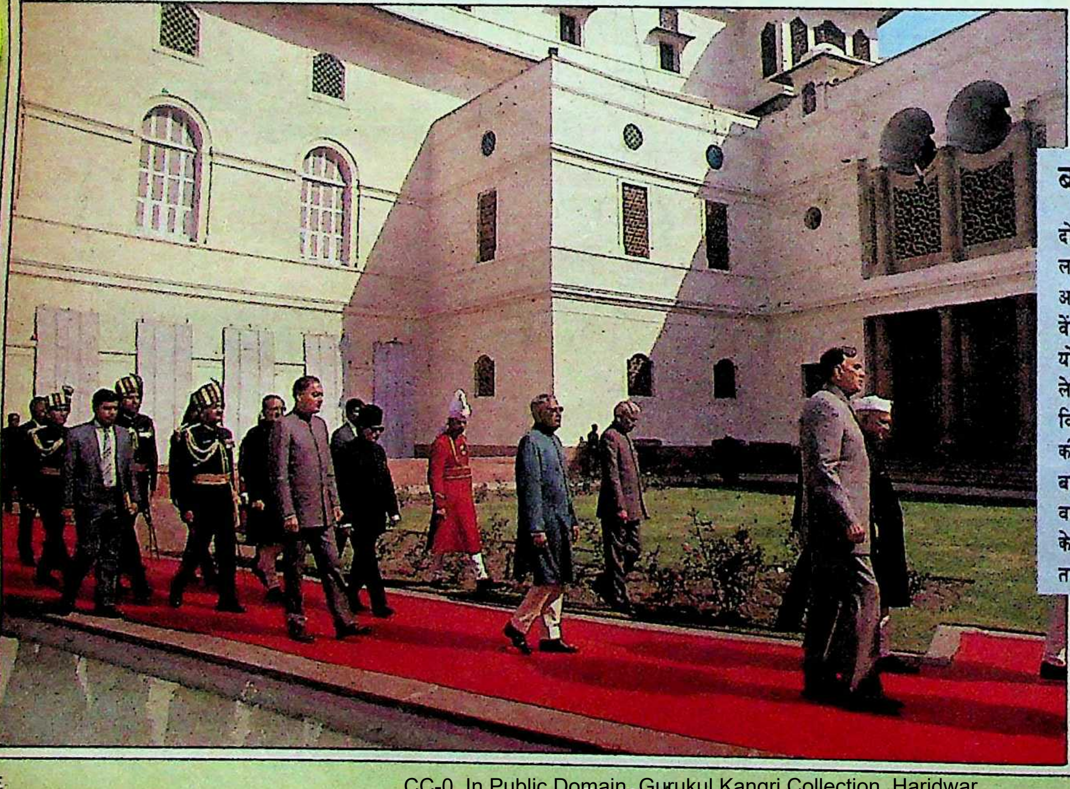

बजट सत्र के पहले दिन २१ फरवरी, १९८९ को संसद के दोनों सदनों की साझी बैठक में लगभग चालीस मिनट के अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने सरकार की भावी योजनाओं का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन सूचना-प्रचार विभाग की विज्ञापन सामग्री की तरह सरकार की उपलब्धियों की सूची पेश की। बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा हर वर्ष होता है। सत्र का उद्घाटन करने के पहले संसद के केंद्रीय कक्ष की तरफ जाते राष्ट्रपति वेंकटरमण।

छाया :
अशोकवाही

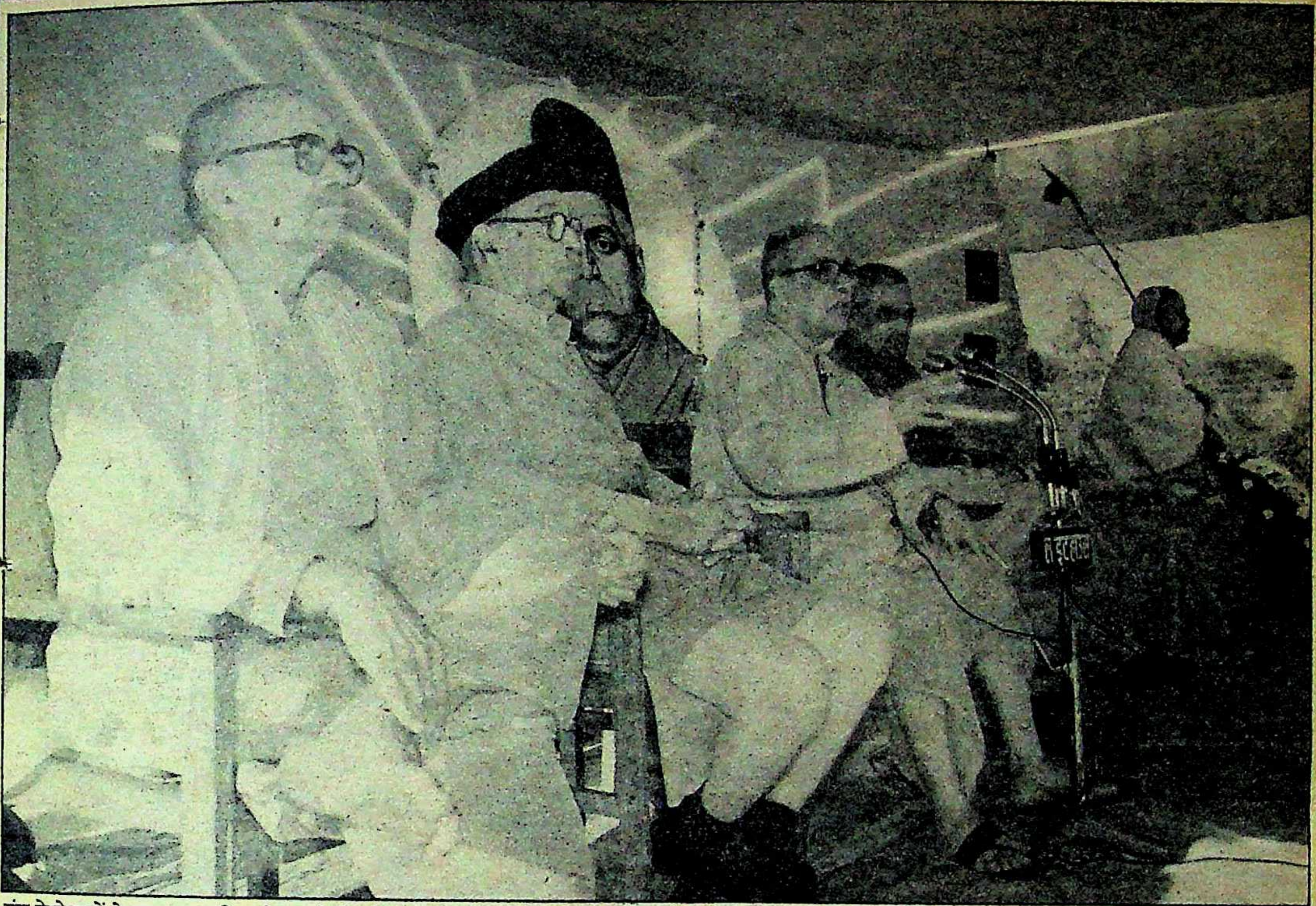

संघ के नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती

लखनऊ हिंदू संगम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक मुहिम

२६ फरवरी को लखनऊ में डा० हेडगेवार की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित हिंदू संगम में भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी तथा शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में संघ ने जो तेवर अपनाया है उससे साफ जाहिर होता है कि आगामी चुनाव में आरएसएस महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। कट्टर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीति का सहारा लेने पर आमादा संघ की रणनीति में क्या कोई मूलभूत परिवर्तन आया है? धार्मिक आधार पर चुनावों में मत देने की संघ की सीख का परिणाम क्या हो सकता है?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में २६ फरवरी को लखनऊ में आयोजित 'विराट हिंदू संगम' संख्या और तेवर दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरएसएस के ६४ वर्ष के इतिहास में यह सबसे बड़ा और प्रभावी हिंदू संगम था। लगभग पचास हजार संगठित गणवेषधारी स्वयंसेवकों और इतने ही उत्साही तथा 'कट्टर' समर्थकों की मौजूदगी में वक्ताओं के चेतावनी भरे भाषण ने सभी राजनीतिक दलों को चिंतित कर दिया है। वास्तव में यह हिंदू संगम, संघ की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की मुखर अभिव्यक्ति था। संभवत: यह पहला मौका था, जब हिंदू एकता के नाम पर राजनीतिक मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी, धर्म के पीठाधीश्वर कांचि कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती तथा सर संघ चालक बालासाहब देवरस एक मंच से, एक सुर में बोले। सबके 'उपदेशों' का मर्म राजनीतिक ही था। जिसकी स्पष्ट प्रतिध्वनि यह थी कि अगले चुनाव में अब हिंदू मतों को बंटने नहीं दिया जायेगा, हिंदुओं का वोट उसी को मिलेगा जो खुले तौर पर हिंदू हितों की वकालत करेगा।

हिंदू संगम क्यों ? : राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के चलते देश भर में तेजी से शुरू हुई सांप्रदायिक कतारबंदी की एक कड़ी के रूप में इस हिंदू संगम को देखा जा सकता है। यह बात दूसरी है कि इस संगम में किसी वक्ता ने दूसरे संप्रदाय की खुली आलोचना न कर, केवल हिंदुओं को संगठित करने पर बल दिया।

आजादी के बाद देश के हिंदुओं को गोलबंद करने की खतरनाक प्रवृत्ति १९८४ में उस समय आयी थी, जब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर अयोध्या की राम जन्मभूमि को मुक्त करने का आंदोलन शुरू किया गया था। उस समय देश भर में स्थान-स्थान पर राम जानकी रथ घुमाये गये थे। इसी आंदोलन के तहत हिंदुओं के दिलों में यह बात बिठाने का काफी प्रयास हुआ था कि हिंदुओं के संगठित हुए बिना भगवान राम को 'सरकारी कैद' से मुक्त नहीं कराया जा सकता है।

राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चलाने के पीछे इरादा यह था कि १९८५ के आम चुनाव से पूर्व हिंदुओं को संगठित कर लिया जाये, लेकिन तभी इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने से जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन न केवल ठंडा हो गया, वरन श्रीमती गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के कारण विश्व हिंदू परिषद द्वारा बोयी गयी सांप्रदायिक फसल इंका ने काट ली। बाद में एक अदालती आदेश से जन्मभूमि का ताला खुल गया।

अब चुनाव फिर नजदीक आ गये हैं। ६ अप्रैल, १९८० को जनता पार्टी से अलग होकर जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अवतार लेने के बाद अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनानी चाही थी, लेकिन उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसे सक्रिय सहयोग देना बंद कर दिया। परिणामस्वरूप उसका जनाधार सिमटने लगा। ऐसी स्थिति में भाजपा को पूर्ववर्ती जनसंघ जैसी साख कैसे वापस दिलायी जाये, इस पर जबरदस्त मंथन शुरू हुआ और अंततः यह तय हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूर्ववर्ती जनसंघ की तरह ही भाजपा के गाढ़े रिश्ते होने चाहिए। उधर राम जन्मभूमि के मसले पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की कथित ढुलमुल व तुष्टीकरण नीति से क्षुब्ध आरएसएस ने पिछले वर्ष अपने नागपुर सम्मेलन में फैसला किया कि हिंदुओं को संगठित करने के 'रचनात्मक कार्य' के साथ-साथ आंदोलनात्मक रुख भी अपनाया जाये। इसी फैसले के तहत डाक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह के बैनर तले देश के विभिन्न स्थानों पर हिंदू संगम आयोजित किये गये। लखनऊ का हिंदू संगम वैसे कहने के लिए तो इसी आयोजन की एक कड़ी था, लेकिन इस आयोजन की सफलता के लिए किये गये अतिरिक्त प्रयास, कुछ और ही कहानी कहते हैं।

वास्तव में, महाकुंभ में आयोजित धर्म संसद के इस फैसले के बाद कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर बनाया जायेगा, संघ और उसके स्वयंसेवकों का उत्साह कई गुना बढ़ गया। लखनऊ का हिंदू संगम महाकुंभ के धर्म संसद की

आरएसएस बनाम सेवादल

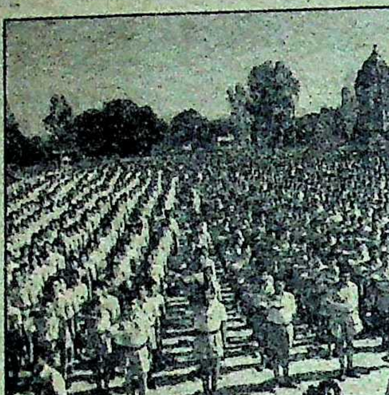

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डा० केशव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस सेवादल के संस्थापक डा० नारायण राव सुब्बाराव हार्डीकर के घनिष्ठतम मित्र थे। यह बात बहुत कम लोगों को ज्ञात है। डा० हेडगेवार और डा० हार्डीकर एक ही गांव के निवासी थे। बचपन से लेकर अंत तक उनकी शिक्षा-दीक्षा एक ही स्कूल व कालेज में हुई थी। यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के दौरान दोनों एक ही जेल में साथ-साथ बंद रहे।

डाक्टर हार्डीकर और डा० हेडगेवार दोनों एक संगठन बनाने के पक्षधर थे जो समाज सेवा और स्वाधीनता की लड़ाई में सहयोग दे सकें। २८ दिसम्बर १९२३ को डा० हार्डीकर ने 'हिंदुस्तानी सेवादल' की स्थापना की, जो बाद में कांग्रेस सेवादल बना। यहीं से उनके और डा० हेडगेवार के बीच वैचारिक मतभेद हो गये थे। डा० हार्डीकर का मत था कि संगठन में सभी धर्मों के लोगों को रखा जाये। पर डा० हेडगेवार एक ऐसा संगठन बनाने के पक्षधर थे, जिसमें मात्र हिंदू धर्मावलंबियों को ही रखा जाये। बस यहीं दोनों मित्रों में मतभेद हो गये और उन्होंने अपने अलग-अलग रास्ते चुन लिये।

सेवादल की स्थापना के लगभग डेढ़ वर्ष बाद १९२५ को विजय दशमी के दिन डा० हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दी। सेवादल और आरएसएस में एक ही तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। बुनियादी फर्क यह था कि संघ पूर्णतया हिंदूवादी संगठन था। अन्यथा लाठी चलाना, परेड करना, प्राकृतिक आपदाओं में जनता की सेवा आदि कार्य दोनों संगठन करते थे। स्वाधीनता के बाद कांग्रेस ने सेवादल की उपेक्षा की और यह संगठन मृतप्राय हो गया। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शाखा के जरिये अपने स्वयंसेवक बनाने का कार्य जारी रखा। १९७७ के आम चुनावों में आरएसएस ने जनता पार्टी का खुल कर सहयोग किया। इसके पूर्व वह अराजनीतिक स्वयंसेवी संगठन होने का दावा करता था। इससे संघ को यह हानि हुई कि इसका राजनीतिक संगठन जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया। इसके बावजूद आरएसएस ने अपना स्वतंत्र स्वरूप बनाये रखकर हिंदू समाज का संगठन जारी रखा और राम जन्मभूमि का मुद्दा उठते ही उसने अपने पैर हिंदूवादी विचारधारा के माननेवालों के बीच जमाने शुरू कर दिये। इस सब के बावजूद संघ में कभी अनुशासनहीनता या राजनीति सामने नहीं आयी।

सेवादल ठीक इसके विपरीत दिशा में लुढ़कता रहा। राजीव गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद सेवादल को पुनर्जीवित किया गया। दिसम्बर '८३ में जब कांग्रेस सेवादल की स्वर्ण जयंती मनायी गयी, तो राजीव गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे। उन्हें काडर (स्वयंसेवक) पर आधारित संगठन बहुत जंचा। फिर क्या था राजीव गांधी के निर्देश पर सेवादल के मृतप्राय संगठन में नयी जान फूंकी गयी। कांग्रेस की यह इकाई राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सक्रिय हो उठी।

अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कांग्रेस सेवादल में अब तक क्या तब्दीलियां आयी हैं ? जहां तक आरएसएस का प्रश्न है, उसकी नीतियां, कार्यप्रणाली और मानसिकता आज भी वही है, जो संगठन के स्थापना के समय थी। लेकिन कांग्रेस सेवादल में दलगत राजनीति और अवसरवादिता ने स्थान ले लिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस ऐलान के बाद कि सेवादल से ट्रेनिंग लेकर आनेवाले सांसदों, कार्यकर्ताओं और विधायकों को चुनावों में पार्टी का टिकट देने में वरीयता दी जायेगी, विभिन्न राजनीतिकों के बीच संगठन पर कब्जा करने की लड़ाई छिड़वा दी। अब हालत यह है कि समाज सेवा का सपना लेकर डा० हार्डीकर द्वारा स्थापित सेवादल राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दूसरी ओर आरएसएस आज भी अपने संस्थापक डा० हेडगेवार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है।

—लखनऊ ब्यूरो

घोषणा पर हिंदुओं की प्रतिक्रिया जानने का एक अच्छा 'बैरोमीटर' था। हिंदू संगम के आयोजकों ने तैयारी के दौरान इस बात का संकेत दिया था कि हिंदू संगम में यह घोषणा कर दी जायेगी कि अयोध्या में प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू, ईंटें पहुंचाना शुरू कर दें। हालांकि हिंदू संगम में ऐसी कोई घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने यह शाप जरूर दे दिया, "राम जन्मभूमि को हिंदुओं से छीनने की ज़ो भी कोशिश करेगा वह जीवित नहीं रह सकेगा।"

इस हिंदू संगम के आयोजन से संघ को यह आकलन करने में सफलता मिली है कि अयोध्या में राम जन्म मंदिर के निर्माण-कार्य में उसे अपार समर्थन प्राप्त होगा। हिंदू संगम के दौरान दिखे तेवर और उन्माद से यह बात भी साफ हो गयी है कि जहां हाल के वर्षों में आरएसएस की संगठन शक्ति में काफी इजाफा हुआ है, वहीं अपने को धर्म निरपेक्ष कहने वाले संगठनों के सामने आरएसएस चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। शायद यही वजह है कि इस हिंदू संगम की सफलता को देखकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के एक पदाधिकारी को ऐलान करना पड़ा, "हम किसी भी कीमत पर वहां मंदिर नहीं बनने देंगे। जल्द ही हम सरकार पर दबाव डालने के लिए इससे भी (हिंदू संगम से) बड़ी मुस्लिम कांफ्रेंस करेंगे ?"

यह एक खतरनाक संकेत है। हिंदू संगम के बारे में शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी समर्थक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी कहते हैं, "यह सिर्फ आरएसएस का मजमा नहीं था। हिंदू वोटों को भुनाने की फिराक में लगे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इस मजमे को कामयाब बनाने का काम परदे के पीछे से किया है। ये कांग्रेसी नेता जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। हम यह सब चलने नहीं देंगे, क्योंकि जवाबी कार्यवाही इससे भी बुरी हो सकती है।"

लेकिन इसके जवाब में डा० हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह के पूर्वी उत्तर प्रदेश समिति के महामंत्री ब्रज मोहनजी का कहना है, "यह हिंदू संगम कतई सांप्रदायिक नहीं था। हमने हिंदू जागरण और एक होकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पहचाने के लिए हिंदुओं का आह्वान किया है। इस हिंदू संगम में राम जन्मभूमि के मुद्दे पर तो बस नाम मात्र की ही चर्चा हुई। यह बात सही भी है। हिंदू संगम में जन्मभूमि के मामले पर जितनी चर्चा की उम्मीद लोगों को थी, उतनी तो नहीं हुई, लेकिन सम्मेलन (हिंदू संगम) स्थल पर लगे संघ ध्वज के ठीक नीचे प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर का एक बड़ा मानचित्र जरूर चमक रहा था।

संघ के नये तेवर : अब आरएसएस के तेवर में काफी बदलाव आ गया है। सर संघ चालक बाला साहब देवरस ने संगम में कहा, "राम जन्मभूमि के मुद्दे पर पूरा हिंदू समाज जागृत हो चुका है। सरकार और विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की नीति अब ज्यादा दिनों तक चलनेवाली नहीं है। वोट देने से पूर्व अब हिंदू एक बार यह जरूर सोचेगा कि उसका हित साधन कौन कर रहा है।"

जनता दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक रूप दिये जाने की मांग की आलोचना करते हुए देवरस ने कहा, "वीपी सिंह वोटों की राजनीति के लिए ही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीति अपना रहे हैं। उन्हें जल्दी ही इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वीपी को अल्पसंख्यक आयोग के बजाय मानव अधिकार आयोग के गठन की मांग करनी चाहिए।" देवरस के इस कथन का साफ संकेत है कि वे अब हिंदू समाज को संगठित करने से ज्यादा, हिंदू मतों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं।

जन्मभूमि विवाद के पहले तक आरएसएस हमेशा यह कहता रहा है कि उसका राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं, उसका काम केवल हिंदुओं को संगठित करने का है, वोट कोई किसी को दे। देवरस ने तो यह तक कहा था कि हिंदू हितों की वकालत करनेवाले कांग्रेसी प्रतिनिधियों को भी वोट दिये जा सकते हैं, लेकिन अब उनकी रणनीति बदल गयी है। आरएसएस का अब इरादा चुनाव के मैदान में सक्रिय भूमिका निभाने का है। संघ के मुख्य उद्देश्य हैं संविधान की धारा ३७० को समाप्त कराना, अल्पसंख्यक आयोग की जगह मानवाधिकार आयोग बनाना, गो हत्या बंद कराना, धर्मांतरण पर रोक लगवाना, हिंदुओं को उनके अधिकार दिलाना। संविधान की धारा २९ व ३० में अल्पसंख्यकों को दिये गये विशेषाधिकारों को समाप्त कराना।

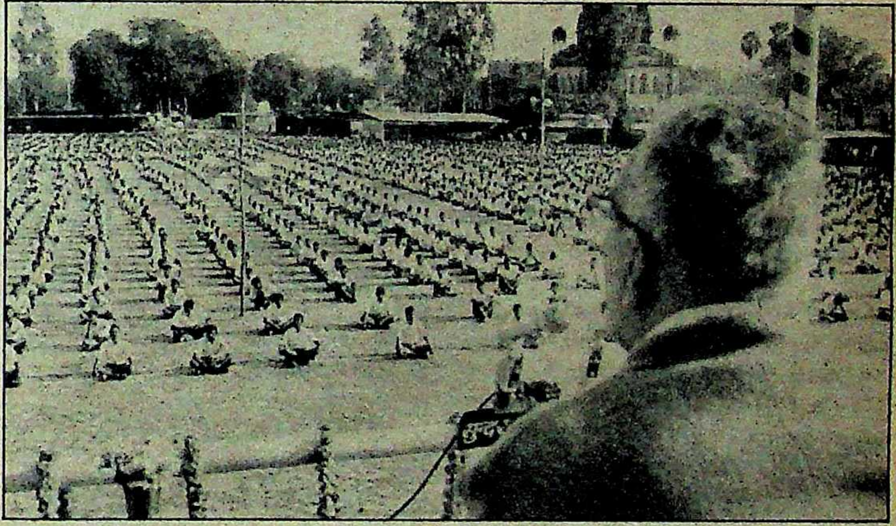
'कट्टरता' की दीक्षा : सर संघ चालक देवरस लखनऊ में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख स्तंभ तथा डाक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह समिति के महामंत्री प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया का साफ कहना है कि जो भी हमारी इन मांगों को मानेगा, हम उसका साथ देंगे। वे कहते हैं, "चूंकि हमारी इन मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा है, अतः हमारा पूरा समर्थन उसके साथ है।"

हिंदू संगम में अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति इस नये बदलते समीकरण का परिचायक है। प्रसंगवश, आरएसएस का धीरे-धीरे राजनीतिकरण तभी शुरू हो गया था, जब १९७३ में गुरु गोलबलकर की मृत्यु के बाद बालासाहब देवरस सर संघ चालक बने। गुरु गोलबलकर के समय तक संघ की प्राथमिकता हिंदू समाज को संगठित करना और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना था। देवरस के नेतृत्व में संघ की प्राथमिकता राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करने में केन्द्रित हो गयी। इस बदले चिन्तन का नतीजा था कि आरएसएस ने आपातकाल के बाद जनता पार्टी का खुलकर साथ दिया था। हालांकि जनता पार्टी अपने अन्तर्विरोधों के कारण टूटकर सत्ताच्युत हो गयी, लेकिन आरएसएस ने जनता पार्टी की विजय को अपने राजनीतिक असर का पैमाना माना था। यही वह दौर था, जब आरएसएस ने उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता के तौर पर अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। तमाम सक्रियताओं के बावजूद आरएसएस की शक्ति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। १९८४ के चुनाव में आरएसएस समर्थित प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई थी।

संघ और उत्तर प्रदेश : इस चुनाव के बाद ही आरएसएस के हाथ संयोग से राम जन्मभूमि का मुद्दा लग गया, जिसने उसकी ताकत को तेज गति से आगे बढ़ाया। इसी के साथ डाक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह के जरिये भी अपनी शक्ति का आकलन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा गया। २६ फरवरी को लखनऊ में हुआ हिंदू संगम डाक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह की पूर्वी उत्तर प्रदेश समिति की ओर से आयोजित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष बैरिस्टर नरेंद्र जीत सिंह और

संगठित हिंदू समर्थ भारत
स्वयमेव मृगेन्द्रता

हिंदू मतों पर नजर: हिंदू संगम का मंच

महामंत्री ब्रज मोहन हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से भी संघ के दो असरदार सम्मेलन हो चुके हैं। २ फरवरी को अलीगढ़ तथा ६ फरवरी को बरेली में संघ के इन आयोजनों में बाला साहब देवरस तथा सत्य मित्रानंद शामिल हुए थे। इन दो सम्मेलनों में संघ के अतिरिक्त अन्य हिंदू संगठनों का गठबंधन तथा धर्म गुरुओं की मंच पर उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि आरएसएस के हिंदू जागरण अभियान में धार्मिक आस्था को भुनाया जा रहा है। लखनऊ के हिंदू संगम में वक्ताओं के उद्‌गार ने तो संघ के राजनीतिक चिंतन को भी उजागर कर दिया है। आरएसएस की वास्तविक शक्ति का अंदाजा हिंदू संगम में जुटी लगभग एक लाख की भीड़ से लगाया जा सकता है, जो केवल डाक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समिति की केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश शाखा की उपलब्धि थी। लखनऊ के हिंदू संगम में सिखों की भागीदारी आरएसएस की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 'राष्ट्रीय सिख संगत' नामक संगठन का आरएसएस से जुड़ना, हिंदू-सिख एकता का प्रतीकात्मक पहलू है। वर्ष १९८६ में गठित 'राष्ट्रीय सिख संगत' की देश में ७३ तथा विदेश में २५ शाखाएं हैं। संगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार शमशेर सिंह का कहना है, "चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू जागरण का प्रतीक है, अतः सिख इससे अलग नहीं हैं।" बालासाहब देवरस का सोच भी यही है। यही वजह है कि पिछले दिनों मेरठ में सैकड़ों हरिजनों को सिख बनाने की घटना को वे धर्मांतरण नहीं मानते। १४ नवंबर '८८ को लखनऊ के सहकारिता भवन में आयोजित गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस समारोह में संघ के अखिल भारतीय महामंत्री प्रोफेसर राजेंद्र सिंह की उपस्थिति इस गठबंधन का परिचायक है। हिंदू संगम के अवसर पर लखनऊ के पांच प्रमुख गुरुद्वारों के प्रमुखों द्वारा बाला साहब देवरस का स्वागत और उनसे हुई गुफ्तगू का अर्थ भी यही है। इस हिंदू संगम के बाद इस बात के भी संकेत मिले हैं कि 'राष्ट्रीय सिख संगत' के सदस्य देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भी शीघ्र ही संघ के मंच पर ले आयेंगे।

भाजपा का बदला सुर: आरएसएस के इस हिंदू संगम में अटल बिहारी वाजपेयी की उपस्थिति तथा उनका यह कथन कम आश्चर्यजनक नहीं रहा कि उन्हें पहले से सूचित किया जाता, तो वे भी गणवेश (हाफ पैंट-कमीज) में आते। इससे पहले आरएसएस के साथ भाजपा या अपने संबंधों के सवाल पर वे कतराया करते थे। पिछले वर्ष नागपुर में आयोजित आरएसएस के राष्ट्रीय सम्मेलन में वाजपेयी की तीखी आलोचना इसीलिए हुई थी कि उन्होंने संघ की भाजपा पर नियंत्रण की मुहिम का विरोध किया था। अब उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी का इस हिंदू संगम में खुलकर संघमय हो जाना भाजपा के पूरी तरह बदले चरित्र और रणनीति का परिचायक है। उन्होंने लखनऊ में इस मंच के जरिये संभवतः पहली बार प्रकारान्तर से यह घोषित किया है कि अब भाजपा, हिंदू मानसिकता और आरएसएस के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ेगी।

भाजपा के इस बदले तेवर की दो वजहें हैं। पहली तो यह कि राष्ट्रीय विपक्षी दलों द्वारा भाजपा की उपेक्षा से यह साफ हो गया है कि विपक्षी राजनीतिक गठबंधन में भाजपा को वांछित जगह नहीं मिलनी है। दूसरी मुख्य वजह यह है कि भाजपा को यह लगने लगा है कि अगला चुनाव राम जन्मभूमि जैसे सांप्रदायिक आधार पर लड़ा जायेगा। मतों का ध्रुवीकरण इस बार पार्टियों के आधार पर नहीं वरन सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर होगा। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्साहपूर्वक अपनायी गयी भाजपा की इस रणनीति का सबसे बड़ा कारण प्रदेश में हाल में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में भाजपा की उल्लेखनीय सफलता है।

भाजपा का बढ़ता प्रभाव: वर्ष १९८४ के चुनाव के बाद भाजपा को एक चुकी पार्टी मान लिया गया था। लेकिन १९८८ में अचानक उसकी बढ़त का प्रकटीकरण इस बात का द्योतक है कि उसे आरएसएस का भरपूर सहयोग मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में वर्ष १९८४ के संसदीय चुनाव में भाजपा ५० सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें ४१ की जमानतें तक जब्त हो गयी थीं। उसका एक भी उम्मीदवार सफल नहीं हुआ। १९८५ के विधानसभाई चुनाव में भी भाजपा को ४२५ में से मात्र १६ सीटें प्राप्त कर संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब भाजपा के तेवर और प्रदेश में उसके अस्तित्व की बढ़त उसकी नयी रणनीति का परिणाम मानी जा रही है।

इस हिंदू संगम में जुटे प्रमुख असरदारों ने प्रदेश भाजपा में चल रही उखाड़-पछाड़ को समाप्त करने पर गम्भीरता से विचार किया। इस समय प्रदेश भाजपा में कई गुट हैं, जो पार्टी पर अपना-अपना प्रभुत्व चाहते हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह सहित कलराज मिश्र और ओम प्रकाश सिंह पार्टी पर अपने-अपने ढंग से हावी होने के जोड़तोड़ में लगे हैं। जनता शासन में उप मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्त का अपना एक अलग गुट है। इसके अतिरिक्त जनता शासन में ही मंत्री रहे हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (वर्तमान विधायक) सहित गंगाभक्त सिंह और लालजी टण्डन भी अपने-अपने गुट को सक्रिय कर रहे हैं। पार्टी के युवा नेताओं में विधान परिषद सदस्य राजनाथ सिंह की पार्टी पर अच्छी पकड़ है। वे मिर्जापुर के निवासी हैं और यह उनके परिश्रम का ही नतीजा था कि स्थानीय निकाय के चुनाव में मिर्जापुर में भाजपा की जीत का प्रतिशत सर्वाधिक रहा।

शायद यही वजह है कि इंका के प्रादेशिक अध्यक्ष बलराम सिंह यादव भी अब यह स्वीकार करने लगे हैं, "मेरी पार्टी को अगले चुनाव में जनता दल से नहीं भाजपा से खतरा है, क्योंकि भाजपा की ताकत जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे हमारी पार्टी के लोगों का चिन्तित होना स्वाभाविक है।"

बहरहाल, लखनऊ का हिंदू संगम कई अर्थों में राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रदेश में वैसे भी जनता दल के घटकों में चल रहा लतिहाव विपक्षी एकता में संशय पैदा करने वाला है। ऐसे में इस चुनावी वर्ष में इस तरह के सम्मेलन स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अगले चुनाव के मतों का ध्रुवीकरण साम्प्रदायिक आधार पर होगा। यह एक खतरनाक प्रक्रिया है, जो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करेगी।

—अजय कुमार और
सुरेश द्विवेदी

छाया: राजेंद्र कुमार

जीवन के रंग अजीब...

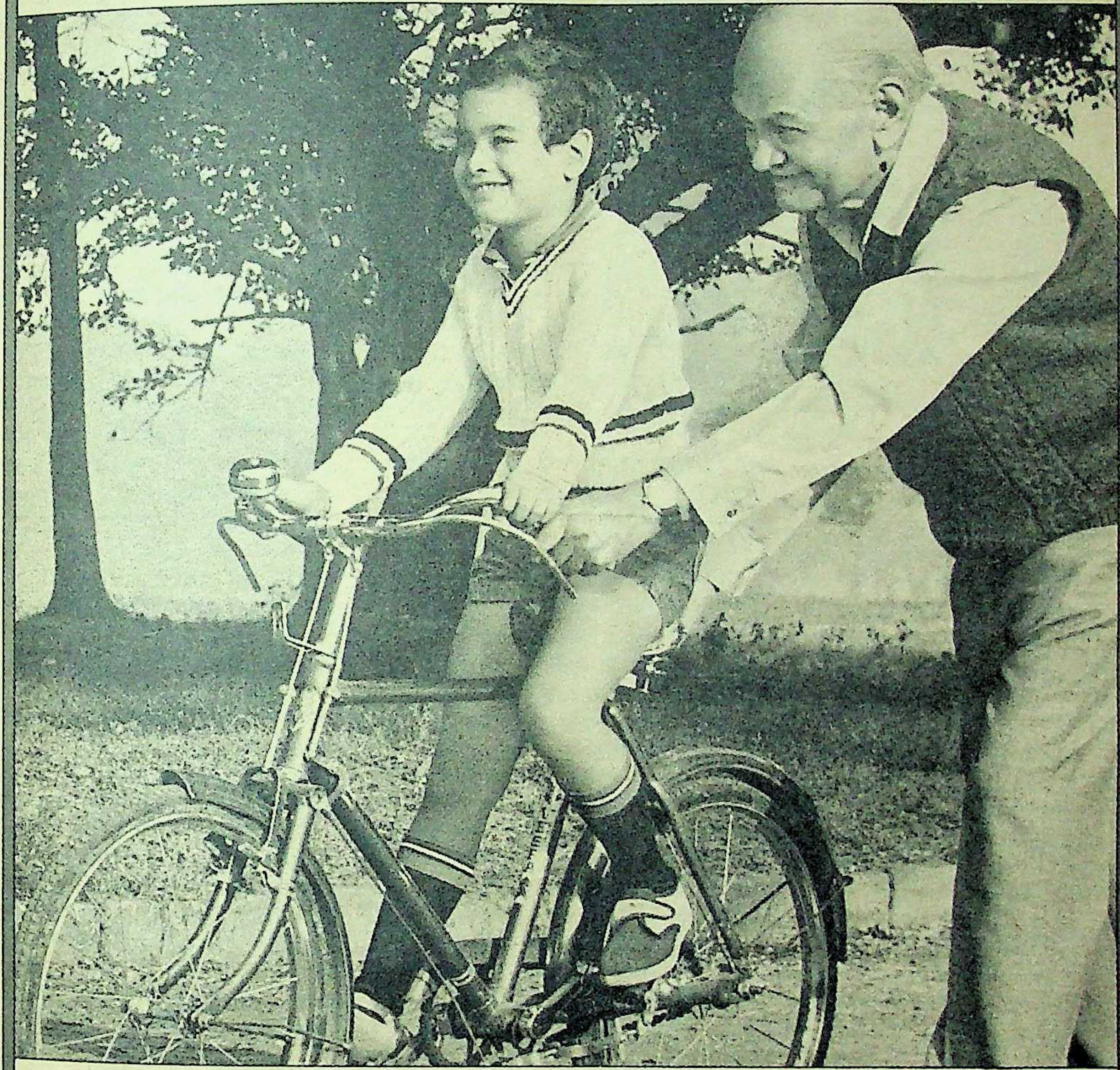

शुक्र है बोरोलीन करीब

खुशबूदार ऐन्टिसेप्टिक क्रीम

BOROLINE
REGD TRADE MARK
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM

सुखी त्वचा और साधारण कटने-छिलने पर अनोखा असर

साठ साल पहले अव्वल, आज भी अव्वल

बोरोलीन प्रसाधन सामग्री नहीं

जी डी फार्मास्युटिकल्स
कलकत्ता ७०००५३

Response 1038

साक्षात्कार/बालासाहब देवरस

वीपी सिंह आग से खेल रहे हैं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक बाला साहब देवरस इन दिनों सुर्खियों में हैं। अब तक संघ के बारे में यह प्रचारित था कि वह केवल सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन है। लेकिन हाल में सर संघ चालक के बयानों से यह साफ नजर आने लगा है कि संघ की परोक्ष राजनीतिक भागीदारी प्रत्यक्ष होने जा रही है। संघ के कार्यक्रमों से लगता है कि वह 'कट्टर' हिंदू मतों को अपने वर्चस्व में लेने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में हुए विराट हिंदू संगम से इसी योजना की पुष्टि होती है। हिंदू संगम और उसके बाद आरएसएस की रणनीति पर 'माया' से उन्होंने खुलकर बातें कीं। प्रस्तुत हैं अंश:

माया: *लखनऊ के हिंदू संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है?*

देवरस: *यह संगम इस बात का द्योतक है कि अब हिंदू जागृत हो चुका है। इस अभियान के माध्यम से हम सरकार को जताना चाहते हैं कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण की नीति बदले। हमारा किसी संप्रदाय विशेष से द्वेष नहीं, लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहां हिंदुओं के हित की ही चर्चा हो।*

माया: *संघ, मुस्लिमों का विरोधी क्यों है?*

देवरस: *संघ के बारे में तमाम भ्रांतियां निहित स्वार्थोंवश फैलायी जाती हैं। यह धारणा गलत है कि संघ, मुसलमान विरोधी है। ऐसा केवल भारत में ही है कि क्रिश्चियन अपने को क्रिश्चियन और मुसलमान अपने को गर्व से मुसलमान कहते हैं, तो किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर हिंदू अपने को गर्व से हिंदू कहे, तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है। अल्पसंख्यक, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों का भारत में खुलकर दुरुपयोग हो रहा है।*

माया: *अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार के उदार रवैये पर आपको आपत्ति क्यों है?*

देवरस: *आपत्ति का कारण यह है कि सरकार ने राष्ट्र के हिन्दू-मुस्लिमों को बांट दिया है। यह सरकार की वोट पाने की नीयत की घिनौनी साजिश है। अल्पसंख्यकों से हमारा कोई दुराव नहीं है। हिंदुस्तान में जब लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो किसी एक वर्ग विशेष के लिए संविधान में अलग व्याख्या क्यों? अपने देश में अल्पसंख्यक घोषित लोगों की अन्य देशों में अच्छी खासी तादाद है, लेकिन वहां तो उन्हें कोई ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, जैसा कि उन्हें हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद २९ और ३० में प्रदत्त है। हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन कर इस विशेषाधिकार को समाप्त कर वर्ग समानता बनायी जाये।*

माया: *इस समय देश में पनपे सांप्रदायिक माहौल का कारण आपकी दृष्टि में क्या है?*

देवरस: *राजनीतिक दलों की वोट प्राप्त करने की स्वार्थी नीति इसका मूल कारण है। समुदाय विशेष के प्रति इन दलों द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाने से दूसरे समुदाय का रोष में आना स्वाभाविक है। सरकार की यही करतूतें दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव को बढ़ावा दे रही हैं। वैसे इस मनमुटाव में स्वयं की विवेकहीनता भी है। राम जन्मभूमि विवाद को इतने दिनों से लटकाये रखना सरकार की वोट नीति ही है। नसबंदी की त्रासदी हिंदू ही भोग रहे हैं। अल्पसंख्यकों की तो संख्या बढ़ ही रही है।*

माया: *सलमान रुश्दी की पुस्तक 'सेटेनिक वर्सेज' पर लगी पाबंदी और रुश्दी की हत्या के फतवे के बारे में आपके क्या विचार हैं?*

देवरस: *इसे मैं असभ्य समाज की बर्बर प्रतिक्रिया मानता हूं। यदि इस पुस्तक में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात लिखी गयी है, जो किसी संप्रदाय विशेष को नागवार गुजरी है, तो इसके जवाब में एक और पुस्तक प्रकाशित कर उसमें इसका खंडन करना चाहिए। लेखक की हत्या का फतवा जारी करना न्यायसंगत नहीं है। भारत में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना सरकार की तुष्टीकरण की नीति का द्योतक है। वैमनस्य के जो बीज अंग्रेजों ने हमारे बीच बोये थे, आज इंका उसी को रोप रही है। देश का बंटवारा इसी नीति का खमियाजा था।*

माया: *राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है?*

देवरस: *यह फैसला अभी नहीं हुआ है। संघ की नीति चुनाव से दूर रहने की है, राजनीति से दूर रहने की नहीं। जहां तक मैं समझता हूं, संघ चुनाव की खिड़की से राजनीति के आंगन तक पहुंचने के पक्ष में नहीं है।*

माया: *इस हिंदू संगम में आपने घोषणा की है कि, जो हिंदू हितों की बात करेगा, हिंदू उसे ही वोट देंगे। क्या इसका अर्थ राजनीतिक नहीं है?*

देवरस: *हमारा संघ हिंदू जागरण और रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता देता है। लेकिन इससे जुड़े लोग मतदाता भी हैं। इनके मतों से हिंदू हितों का ध्रुवीकरण आगामी चुनाव की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा। वैसे, अब यह तय है कि अपने मताधिकार के प्रति हिंदू जागृत हो चुका है और ये मत उसी के खाते में जायेंगे जो तुष्टीकरण की नीति छोड़कर हिंदू हितों की बात करेगा।*

माया: *पिछले वर्ष कांग्रेस के पक्ष में आपके एक बयान को लेकर खासा विवाद उठा था, सचाई क्या थी?*

देवरस: *समूची बात को तोड़-मरोड़ कर प्रचारित किया गया था। मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि कांग्रेस में झगड़े और टूटन के बावजूद आसन्न चुनावों से पहले उसका विकल्प उभरता नजर नहीं आता। प्रतिपक्ष शासित प्रदेश तो है, पर प्रतिपक्ष का अभी कोई अखिल भारतीय रूप नहीं उभरा।*

माया: *तो क्या इसका मतलब यह है कि आप भाजपा को अक्षम मानते हैं?*

देवरस: *नहीं। भाजपा का प्रभाव दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में है और अब तो उत्तर प्रदेश में भी इसकी पैठ बन रही है। भाजपा का भविष्य उज्ज्वल है।*

माया: *शिवसेना और संघ के संबंध का स्वरूप क्या है?*

देवरस: *हिंदू समाज में जागृति आयी है। शिवसेना ही क्या, देश के अन्य सभी हिंदू संगठन हमारे साथ हैं। ये सभी हिंदू शक्ति के परिचायक हैं। हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय है। शिवसेना ने महाराष्ट्र में भूमिपुत्र का नारा लगाया। हम तो यही कहेंगे कि जब कोई हिंदू सोच स्वीकार करता है, तब राष्ट्र को सामने रखकर सोचे, सिर्फ बंबई या महाराष्ट्र तक बंधकर क्यों रहे?*

माया: *कम्युनिस्टों के बारे में आपकी राय?*

देवरस: *हम उन्हें महत्व नहीं देते। उनके पैर तो अब रूस और चीन से भी उखड़ने लगे हैं। कम्युनिस्टों को अब भय है कि हम (संघ) जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें वैसे-वैसे पीछे हटना पड़ेगा।*

माया: *वीपी सिंह के बारे में आपके विचार?*

देवरस: *वीपी सिंह भी कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी यह कोशिश सफल नहीं होने देंगे। वीपी सिंह अल्पसंख्यक आयोग बनाये रखने की बात कर रहे हैं। यह वही वीपी सिंह हैं, जिन्होंने मुस्लिम वोट कटने के भय से इलाहाबाद चुनाव में आरिफ मोहम्मद खान को न बुलाकर शहाबुद्दीन का सहारा लिया था। वास्तव में वीपी सिंह आग से खेल रहे हैं।*

—अ०कु०/सु०द्वि०

जनतादल

घटकवाद की घुटन

जनमोर्चा, लोकदल और जनता पार्टी ने अपना नाम मिटा कर 'जनता दल' के नाम से एक दल तो बना लिया, लेकिन तीनों दलों के नेताओं के स्वार्थ और अहं आपस में टकरा रहे हैं। दल के प्रदेश अध्यक्षों के चयन के समय यह टकराहट तेजी से उभर कर आयी है। जनता दल में यह घटकवाद क्या रूप लेता जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे?

चन्द्रशेखर और देवीलाल

फूट का नमूना: जद कार्यालय के सामने प्रदर्शन

"जनता दल तो बन गया है अब नेता दल की 'प्रूनिंग' (कटाई-छटाई) का काम जारी है। जो अपने आप इस्तीफा दे रहे हैं वे स्वाभाविक 'प्रूनिग' कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जो कोई रूसता (नाराज) है, तो दूसरे खुश होते हैं।" 'माया' से एक विशेष भेंट के दौरान देवीलाल द्वारा की गयी यह टिप्पणी जनता दल में व्याप्त उठापटक, खींचतान, तनाव, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा और विद्वेष को पूर्णतया उजागर करती है।

१९९० में दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराने का स्वप्न संजोनेवाले जनता दल का मुख्य लक्ष्य कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरने की जगह व्यक्तिगत हित-लाभ साधना ही प्रतीत होता है। इसका उदाहरण दल के गठन के महीनों बाद प्रदेशाध्यक्षों के चयन के लिए आयोजित संसदीय बोर्ड की बैठकें रही हैं। पहली बैठक में मप्र अध्यक्ष के चयन के मुद्दे पर तो प्रचुर हायहत्या हुई ही, बिहार तक पहुंचते-पहुंचते गाड़ी मानो दलदल में ही फंस गयी। दूसरी बैठक में तू-तू, मैं-मैं इस कदर बढ़ी कि स्वयं दल के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल की तानाकशी के फलस्वरूप बैठक से बाहर चले जाने को बाध्य हो गये। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएन गाडगिल के अनुसार, "कांग्रेस के १०३ वर्ष पुराने इतिहास में कभी ऐसी अशोभनीय घटना देखने को नहीं मिली।"

यही नहीं अजीत सिंह घटक के असंतुष्टों ने २३ फरवरी को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपने ही दल के वरिष्ठ नेताओं चंद्रशेखर, देवीलाल और दल के उप्र के नये अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध जिस प्रकार की नारेबाजी की वह भी अपने में अभूतपूर्व थी। पार्टी के आंतरिक कटाजुज्झ के लिए विख्यात दल के उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े की बिहार में मौजूदगी में नवनियुक्त अध्यक्ष रघुनाथ झा और दूसरे प्रत्याशी श्याम सुंदर दास के समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत तो आयी ही, साथ ही अजीत घटक द्वारा दल से बाहर जाने की धमकियां भी निरंतर दी जा रही हैं। स्थिति बंगाल में भी कुछ भिन्न नही रही। तनातनी की अंदर-ही-अंदर सुलगती आग से अन्य प्रदेश भी मुक्त नहीं।

तनातनी का कारण: इस विषम परिदृश्य का मुख्य कारण तीन दलों के विलय से बने इस नवगठित दल में व्याप्त जबरदस्त घटकवाद है। इसका आलम यह है कि जनता दल के ही एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, "दल में सम्मिलित जनता पार्टी घटक खुद तीन खेमों में विभाजित है—चंद्रशेखर, अजीत सिंह और हेगड़े खेमा। लोकदल में देवीलाल बहुगुणा को 'धूल चटाने' की अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने में तो सफल रहे हैं, किंतु अपने ही सपूतों-दल के हरियाणा प्रदेश के नये अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला और विधायक रणजीत सिंह—के दो राज्यव्यापी खेमों को एक करने में पूर्णतया नाकाम रहे हैं। रही जनमोर्चा की बात तो इसका तो हर नेता स्वयं में एक घटक है।"

आपसी संघर्ष की आग में घी का काम प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की दिनोदिन घटती लोकप्रियता के परिणामस्वरूप नजदीक दिखायी देती सत्ता ने किया है। ऐसे हालात में हर घटक भावी सत्ता के बंटवारे में अपना अधिकाधिक दावा पेश करने की अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। इसी कारण यद्यपि कहने को तो विलय से एकीकृत दल का गठन हो गया है, किंतु नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन आज भी मिले नहीं हैं। वर्षों के संस्कार, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा, संदेह, संशय और कटुता के रातोरात लोप होने की अपेक्षा करना तो व्यावहारिक भी नहीं है, किंतु अफसोस तो यह है कि कारगर एकता के लिए अपेक्षित तालमेल भी वरिष्ठ नेताओं की चिरपिपासु महत्वाकांक्षा, अहं की टकराहट और कुरसी की लालसा के चलते संभव नहीं हो पाया है। केंद्र में ऊर्जा राज्यमंत्री कल्पनाथ राय व्यंग्य करते हुए बोले, "विपक्ष में तो तथाकथित 'मरजर' (विलय) हुआ है वह इनके खुदबखुद मरने और जलने के लिए ही है।"

व्यक्तिगत लाभ: जनता दल की विडंबना यह है कि इसका गठन ही विघटन से हुआ। फिर गठन के बाद भी व्यापक जूतमपैजार रुकी नहीं। इसका कारण सिर्फ यह है कि हर घटक और हर नेता पदों की बंदरबांट के लिए लगातार जुटा रहा है। शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रश्न पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर काफी थुक्का-फजीहत के बाद सहमति अवश्य हुई, पर यह भी सतही लगती है। पदों की प्राप्ति और अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए उचित-अनुचित हर हथियार इस्तेमाल किया गया है। सबसे अधिक कारगर हथकंडा दबाव की रणनीति का रहा है। इससे स्वयं पार्टी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बरी नहीं बताये जाते। अनिर्णय की मनोदशा में ग्रस्त रहने के लिए विख्यात वीपी सिंह अपने ही साथी- संघातियों द्वारा उत्पन्न मुसीबतों के कारण जब-तब प्रधानमंत्री पद का दावेदार न होने का जो ऐलान करते हैं वह उनकी दबाव की अपनी कूटनीति का विशिष्ट नमूना है। पार्टी अध्यक्ष यदि इस हथकंडे का कभी-कभार उपयोग करते हैं, तो अन्य नेता और घटक लगभग हर मुद्दे और समय पर यही रवैया अपनाते हैं। इसके चलते चंद्रशेखर बैठक में शामिल न हो अपनी असहयोग की चिरपरिचित शैली का उपयोग करते हैं कि यदि मेरी निर्णय लेनेवाली जमात में कोई गिनती नहीं, तो मेरी उपस्थिति-अनुपस्थिति से क्या फर्क पड़ता है? देवीलाल अपनी अलग सभायें आयोजित कर थैली और अपना मुंह खोल पार्टीजनों पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रहार कर अपना वर्चस्व स्थापित करने का पूरा माहौल बनाते हैं। इन दिग्गजों के बीच अपेक्षाकृत कम राजनीतिक अनुभव वाले अजीत सिंह स्वयं आगे न बढ़ने में यदि हिचकिचाये भी हैं, तो उनके घटक ने जनता दल से बाहर होने का दबाव जब तब डाल कर कसर पूरी कर दी है।

संप्रति भारतीय राजनीति का तो यह हाल है कि बाजी हरहाल में अपने हक में करने की रणनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। आज जिसे गले लगाया कल उसकी पीठ में छुरा भोंकना सर्वस्वीकृत शैली सी प्रतीत होती है। कल तक के जानी दुश्मन हेगड़े और अजीत सिंह आज विश्वनाथ प्रताप सिंह के झंडे तले लामबंद हैं, तो देवीलाल द्वारा एक समय कांग्रेसी एजेंट करार दिये जानेवाले चंद्रशेखर आज उनके ही सगे और सलाहकार बन गये हैं। इन्हीं रातोरात बदलते रिश्तों को वर्तमान उथल-पुथल और आंतरिक संघर्ष के लिए दोषी माना जा रहा है। तीव्र असंतोष और गुत्थमगुत्था का मुद्दा मुलायम सिंह का उप्र में और रघुनाथ झा का बिहार में क्षत्रप बनाया जाना है। देश के इन सर्वाधिक मतदाताओं और सीटोंवाले दो राज्यों में न केवल जनता दल का विस्तृत जनाधार है, बल्कि भावी चुनावी महाभारत में यही प्रदेश निर्णायक भूमिका भी निभायेंगे। अतः दल का हर घटक और सूबेदार यहां अपने पांव मजबूती से जमाने के लिए उद्यत है। भले इसके लिए अपनी ही पार्टी की जड़ क्यों न खोदनी पड़े?

दावे अपने-अपने: उप्र और बिहार के पार्टी अध्यक्षों के चयन से असंतुष्ट अजीत सिंह घटक का दावा है कि ये निर्णय न केवल अनुचित हैं, बल्कि चंद्रशेखर, देवीलाल और अरुण नेहरू की साठ-गांठ के नतीजे हैं। इस घटक का दावा है कि इन दोनों प्रदेशों में उनको सर्वाधिक जनसमर्थन प्राप्त है। घटक के एक वरिष्ठ नेता ने 'माया' से बातचीत में कहा, "हमसे राय-सलाह तक नहीं ली गयी। यद्यपि दल के अध्यक्ष से हमें इस संबंध में बराबर आश्वासन मिलते रहे थे।" आश्वासन कितना मिला था यह कहना तो मुश्किल है, किंतु यह अवश्य है कि उप्र के सिपहसालार के बारे में फैसला लेते वक्त पार्टी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुंह खोलने तक का मौका नहीं दिया गया। बिहार के मुद्दे पर जब उन्होंने प्रयास किया, तो स्थिति ऐसी अशोभनीय हो गयी कि पार्टी अध्यक्ष को बैठक से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा।

मुलायम सिंह पर जहां कुछ लोग राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ उनकी सबको साथ न लेकर चल पाने की अक्षमता की शिकायत करते हैं। इसके विपरीत मुलायम सिंह समर्थकों का दावा है कि राज्य में पार्टी की जड़ मजबूत करने और चुनाव जिताने की कबिलीयत मुलायम सिंह के अलावा किसी अन्य विपक्षी नेता में नहीं है। रही बिहार के नवनियुक्त पार्टी अध्यक्ष रघुनाथ झा की बात तो उनकी वफादारी पर ही उंगली उठायी जाने लगी है। उन पर कांग्रेस से पाला बदल कर हाल में जनता पार्टी में शामिल होने, जगन्नाथ मिश्र का अब भी करीबी होने और कांग्रेस मंत्री के रूप में पूर्व में पद से हटाये जाने के खुले इलजाम लग रहे हैं। किंतु उनके समर्थकों के अनुसार बिहार में पार्टी को विजयी बनाने में मात्र वे ही कामयाब हो सकते हैं।

मतभेद: मुलायम सिंह और वीपी सिंह

उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह और अजीत सिंह गुट लंबे अर्से से एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाता। इसी कारण अजीत गुट ने उन्हें उप्र के विपक्षी नेता पद से अपदस्थ करा दिया था। स्पष्ट है कि अजीत गुट को आशंका है कि मुलायम सिंह उनसे अपना पुराना हिसाब अवश्य चुकायेंगे। इसलिए मुलायम सिंह का मार्ग अवरुद्ध करना और उन पर अंकुश लगाने का प्रयास अजीत गुट के लिए लाजिमी है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुलायम सिंह के रिश्तों का इतिहास भी विशेष मधुर नहीं रहा है। वीपी सिंह के उप्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुई सर्वाधिक पुलिस मुठभेड़ें मुलायम सिंह के इलाके में ही हुई थीं। तब से दोनों के बीच गहरी खाई पैदा हो गयी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार इस पृष्ठभूमि में विश्वनाथ प्रताप सिंह का अजीत गुट को ढाड़स बंधाना उतना ही स्वाभाविक रहा जितना कि यह योजना बनाना कि दोनों गुटों की लड़ाई में अपने उम्मीदवार (राजमंगल पांडे) को गद्दीनशीं करवाना।

राजनीति के पुराने खिलाड़ियों—चंद्रशेखर और देवीलाल—को यह खेल भांपते देर नहीं लगी। जनता दल में हाल में ही दाखिला लेनेवाले राजमंगल पांडे की राज्यव्यापी सक्रियता का शायद यही मूल कारण था। मप्र में अपने उम्मीदवार रघु ठाकुर को अध्यक्ष बनाने में विफल देवीलाल एक बार फिर हार का मुंह देखने को तैयार नहीं थे। उल्लेखनीय है कि देवीलाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानी। यद्यपि जनमोर्चा सूत्रों का दावा है कि वीसी शुक्ला की तुलना में रघु ठाकुर कहीं नहीं खड़े होते। देवीलाल की मप्र की बैठकों को आयोजित करने के अलावा उनकी कबिलीयत नहीं है।

देवीलाल के एक निकट सूत्र के अनुसार, "हमारे चौधरी से जमीन की लड़ाई तो कोई जीत नहीं सकता। किंतु मेज की लड़ाई में वे तब उन्नीस पड़ जाते हैं, जब जरूरत होती है सोनारी की और वे करते हैं लोहारी।" अपनी इस कमजोरी को ढांपने के लिए ही चौधरी ने चंद्रशेखर के साथ समीकरण बनाने और संसदीय बोर्ड की तीसरी बैठक में उनकी शिरकत की बाकायदा योजना बनायी।

समीकरण कैसे बदला: विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि दोनों में यह आपसी समझौता हो गया था कि उप्र में चंद्रशेखर देवीलाल के और बिहार में देवीलाल चंद्रशेखर के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। इस प्रकार एक-और-एक जुड़कर वे ग्यारह हो जायेंगे। योजना को अधिक पुख्ता करने के लिए संसदीय बोर्ड की उक्त बैठक की एक बैठक से पूर्व एक गुपचुप बैठक में जनमोर्चा नेता अरुण नेहरू से भी इस बिना पर समझौता कर लिया गया कि यदि वे उप्र और बिहार के मुद्दों पर टांग नहीं अड़ायेंगे, तो वे जम्मू कश्मीर में उनके और मुफ्ती सईद के उम्मीदवार को निर्विरोध नेता बना देंगे।

उप्र और बिहार के लिए इतनी मेहनत-मशक्कत और जोड़तोड़ करने के पीछे मंशा दोहरा था। पाला बदल कर विश्वनाथ प्रताप सिंह की गोद में जा गिरे अजीत सिंह की 'दगाबाजी' से विक्षुब्ध चंद्रशेखर यदि उन्हें सबक सिखाने को आतुर थे, तो देवीलाल और उनके (अजीत सिंह के) जनाधार समान होने के कारण देवीलाल अपने प्रभावक्षेत्र में हरसंभव वृद्धि करने के आकांक्षी थे। साथ ही चंद्रशेखर व देवीलाल दोनों की यह हार्दिक इच्छा है कि यदि वे भावी प्रधानमंत्री न भी बन पायें, तो इस पद पर शोभित होनेवाले विश्वनाथ प्रताप सिंह को कम-से-कम अपनी मुट्ठी में अवश्य रखें। वरना इस गुट के अनुसार उनका (राजा का) एकाधिकार हो जायेगा। जब एकछत्र साम्राज्य की बात शरद यादव से चली, तो वे आगबबूला हो गये। बोले, "यह कांग्रेस का तंबू नहीं है, जो एक बंबू (नेता) पर खड़ा हो। जनता दल एक शामियाना है, जो अनेक मजबूत खंभों पर आश्रित है। इसमें किसी के एकाधिकार का सवाल ही नहीं उठता और इसी स्थिति का कदाचित हर खंभा अपना महत्व व मजबूती जताने के लिए प्रयासरत है।"

अवसरवाद: प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अजीत गुट तो असंतुष्ट है ही जनमोर्चा भी इस समूचे प्रकरण से विक्षुब्ध है। हां, कारण दोनों के अवश्य अलग-अलग हैं। जनमोर्चा अपने नेता व पार्टी अध्यक्ष की छीछालेदर और अवमानना किये जाने से विक्षुब्ध है ही साथ ही, उसे इस बात की भी चिंता है कि घटकवाद और अवसरवादी गठजोड़ के जरिए गलत निर्णय हुए भी हैं और भविष्य में भी किये जा सकते हैं जिसकी गवाह हाल की अशोभनीय घटनाएं रही हैं। अजीत गुट का रोना उप्र और बिहार में अपने घटक से किये गये अन्याय को लेकर है। अपनी बात पहुंचाने के लिए दबाव की राजनीति के तहत गुट के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने विद्रोह का झंडा उठा अपने इस्तीफे दे दिये हैं। यही नहीं, अजीत सिंह समर्थकों ने ऐलानिया यह कहना भी शुरू कर दिया है, "अब जनता दल में सम्मान से रहने की गुंजाइश दिनोदिन कम होती जा रही है, क्योंकि कोई भी मजबूर नेता मजबूत दल नहीं बना-चला सकता।"

अजीत सिंह ने ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया इसलिए राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि यद्यपि वे समझौते की ओर अग्रसर हैं, किंतु उनका घटक दबाव की रणनीति का सहारा लेकर अन्य पदों की बंदर बांट के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहता है। विशेषकर इसलिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह से यह अपेक्षा करना कि वे लिये गये फैसलों—चाहे उनके लिए 'हाईजैकिंग' की तकनीक ही क्यों न इस्तेमाल की गयी हो—को वापस लेंगे, मुमकिन नहीं। दल में बने रहने की उनकी जो मांगें व शर्तें हैं वे इस तथ्य को मद्देनजर रखकर पेश की गयी हैं। उल्लेखनीय है कि उनकी सबसे प्रमुख मांग प्रदेशाध्यक्ष के अधिकारों को सीमित करने की है। इसके लिए उनका प्रस्ताव है कि प्रदेशाध्यक्ष जिला पदाधिकारी व टिकट वितरण आदि के संबंध में जो भी निर्णय लें उसमें विधायक दल के नेता, प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और महासचिव की सर्वसम्मति हो। यदि प्रदेश में सर्वसम्मति संभव न हो, तो अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लें। ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हरिजनों, पिछड़े वर्गों व महिलाओं को देने की पूर्व घोषणा की जो हाल की नियुक्तियों में सरासर अवहेलना हुई है उसका शेष पदों के निर्वाचन में विशेष ध्यान देने की मांग भी की गयी है। तीसरी अहम मांग संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन करने की है। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्षों को संसदीय बोर्ड से अलग करने की मांग की गयी है। तर्क यह दिया जा रहा है कि टिकटों के बंटवारे के समय प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ कोई शिकायत हुई, तो वह केंद्रीय संसदीय बोर्ड में ही आयेगी। यदि प्रदेश अध्यक्ष भी वहां (केंद्रीय संसदीय बोर्ड में) मौजूद हुआ, तो शिकायतकर्ता को न्याय कैसे मिलेगा? इस घटक के नेताओं का मानना है कि उनकी मांगों से पार्टी अध्यक्ष व जनमोर्चा काफी हद तक सहमत हैं। साथ ही, इस बारे में कदम उठाने का आश्वासन भी दिया गया है।

असंतोष ही असंतोष : जहां तक संसदीय बोर्ड का प्रश्न है उसके वर्तमान स्वरूप और प्रक्रिया से केवल अजीत गुट ही नहीं लगभग हर घटक और ईमानदार नेता असंतुष्ट है। भारी-भरकम २२ सदस्यीय संसदीय बोर्ड में किसी निर्णय के पूर्व सौदेबाजी मतभेद और विलंब की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार माकूल फैसले भी अवरुद्ध होते हैं। यही नहीं, पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि के मामले जिस प्रकार संसदीय बोर्ड में पेश होने लगे हैं उससे वह संसदीय बोर्ड की अपेक्षा स्टीयरिंग कमेटी (संचालन समिति) अधिक प्रतीत होती है।

संसदीय बोर्ड के ही एक वरिष्ठ सदस्य ने 'माया' का ध्यान उस गलत परंपरा की ओर भी दिलाया जिसके तहत संसदीय बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष पदों के प्रत्याशी बनने के बाद भी उसी बैठक में मौजूद रहते हैं जिसमें उनके बारे में निर्णय लिए जाते हैं। नतीजतन उम्मीदवार के गुण-अवगुणों के आकलन के समय या तो सदस्यों का मुंह सिल जाता है अथवा उनके मध्य कटुता बढ़ जाती है।

दल के अधिकांश नेताओं का मानना है कि असंतुष्टों द्वारा चाहे कितनी ही जोड़तोड़ की जाये, किंतु तोड़फोड़ कोई भी पसंद नहीं करेगा, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि कोई भी राजनीतिक आत्महत्या करना पसंद नहीं करेगा।

दल में जारी घटकवाद, उठापटक और गलत परंपरा आदि के संबंध में स्वयं पार्टी अध्यक्ष वीपी सिंह दोषी करार दिये जाते हैं। एक वरिष्ठ जनता दल सांसद ने 'माया' से कहा, "गत ११ अक्तूबर के बंगलौर अधिवेशन ने मात्र संविधान संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था। शेष समस्त अधिकार पार्टी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह को सौंप दिये गये थे। वैसे भी जनता पार्टी के जिस संविधान को जनता दल ने अपनाया है उसमें अध्यक्ष वस्तुतः सर्वाधिकार संपन्न है। किंतु स्थिति यह है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने और दल को नयी दिशा देने की जगह वीपी सिंह ने आम सहमति पर जोर देना शुरू कर दिया है। वीपी सिंह के इस अतिलोकतंत्रवाद ने उन्हें सर्वसम्मति और बहुमत का कैदी बना दिया है। क्योंकि सर्वसम्मति में वहां गणित का खेल और सवाल तो उठ खड़ा होता ही है तिकड़मों और तेवरों को भी महत्व मिलता है।" विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा अपनायी गयी इस नीति के पीछे एक पर्यवेक्षक एक विशिष्ट राजनीति और रणनीति देखते हैं। उनका मत है कि संघर्षों और विवादों से बरी हो कर वीपी सिंह अपनी ईमानदार, निष्पक्ष व लोकतांत्रिक छवि बरकरार रखें, ताकि पार्टी में जारी घटकवाद का लाभ भी अंततः उनके ही खाते में जाये। ठीक विपरीत मत राजा समर्थक सांसद जयपाल रेड्डी का है। उनका मानना है कि मनमानी करनेवाले तानाशाह नेता की अपेक्षा उनकी (विश्वनाथ प्रताप सिंह की) का एक निष्पक्ष ब्रोकर (मध्यस्थ) की मौजूदा भूमिका ही सार्थक और फलदायी है।"

कौन-सा रुख और कौन-सा रवैया कब और कितना फलदायी होगा यह तो समय ही बतायेगा, किंतु हालत यह है कि घटकवाद जनता दल के लिए एक स्थायी रोग बनकर उसे दिनोदिन जर्जर करता जा रहा है। हालांकि अब तक के बनते-बिगड़ते समीकरण कूटनीतिक अधिक रणनीतिक कम रहे हैं। किंतु जिस ढंग से देवीलाल और चंद्रशेखर का गठजोड़ हुआ है उससे ऐसा लगने लगा है कि घटकवाद को स्थायित्व प्राप्त हो रहा है। कहा जाता है कि इस गठजोड़ में ओमप्रकाश चौटाला की मध्यस्थता अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। इनाम के तौर पर ही चंद्रशेखर ने चौटाला को पार्टी की हरियाणा की सूबेदारी प्राप्त कराने में भरपूर मदद की है। उल्लेखनीय है कि चौटाला की उम्मीदवारी का विरोध न केवल उनकी ही पार्टी के भीतर था, बल्कि उनके परिवार में भी था। यदाकदा हरियाणा के मंत्री परमानंद का नाम जो उछला उसका समर्थन किसी और ने नहीं उनके छोटे भाई रंजीत सिंह ने एक हरिजन को अध्यक्ष बनाये जाने के नाम पर किया। किंतु दिलचस्प तथ्य यह रहा कि अन्य सभी घटकों ने चौटाला का समर्थन किया। जब इस संबंध में 'माया' ने जनता दल के एक वरिष्ठ नेता से चर्चा की तो उनका दो टूक उत्तर था "चौटाला न सिर्फ एक नायाब संगठनकर्ता हैं, बल्कि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें अड़ियल देवीलाल को नियंत्रण में रख सकने की कूवत है। इसी कारण हमने उनको वहां का अध्यक्ष बनाने में अपनी और दल की खैरियत समझी।"

दल के अधिकांश नेताओं का मानना है कि असंतुष्टों द्वारा चाहे कितनी ही जोड़तोड़ की जाये, किंतु तोड़फोड़ कोई भी करना पसंद नहीं करेगा विशेषकर राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि कोई भी राजनीतिक आत्महत्या करना पसंद नहीं करेगा। तैश में आकर चंद्रशेखर भले ही कह दें कि वे आज भी पार्टी तोड़ सकते हैं अथवा अजीत सिंह अपना अलग घरौंदा बनाने की बात करें, किंतु सचाई यह है कि जनमत के दबाव के चलते कोई भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। स्वयं देवीलाल ने स्वीकारा, "यदि देवीलाल भी बाहर जायेगा, तो मारा जायेगा।" जयपाल रेड्डी ने जोड़ा "सबको लाइन में रखने के लिए बहुगुणा की दुर्गति और हरियाणा का सबक जगजाहिर है।"

मौजूदा तोड़फोड़ और कोटरबंदी में कदाचित सबसे अधिक घाटे में जनता जनार्दन रही है। लोकतांत्रिक प्रणाली के बावजूद ४ दशकों से अधिक समय से एक ही परिवार की हुकूमत खतम होने और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक कारगर विकल्प उभरने की बलवती संभावना पर तुषारापात होता नजर आ रहा है। जनता दल के आपसी संघर्ष, प्रतिद्वंद्विता और आपाधापी से मतदाता कांग्रेस और राजीव की ओर यदि पुनः आशाभरी निगाहों से ताकें, तो उन्हें कुसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। एक शीर्षस्थ नेता तथा एकजुट पार्टी ही मतदाता की शर्त और पहली पसंद होती है। ऐसी स्थिति में देश की बागडोर संभालने का ख्वाब देखनेवाले जनता दल के लिए कम-से-कम अपने घर को सुव्यवस्थित और एकबद्ध करना अपरिहार्य है।

स्वयं जनता दल नेताओं का भी मानना है कि आवश्यकता आज कड़ाई से अनुशासन लागू करने की है। जब इसकी चर्चा विश्वनाथ प्रताप सिंह से चली तो वे बोले, "कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह कहां?" प्रश्न यह है कि विपरीत दिशाओं में भागते घोड़ों वाले इस रथ को क्या सारथि एक सुनिश्चित मार्ग पर रख पायेगा? सारथि यदि असमर्थ सिद्ध हुआ, तो इस चुनावी वर्ष में जनमत की चाबुक कारगर सिद्ध होगी। **—रंजना कक्कड़,**

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

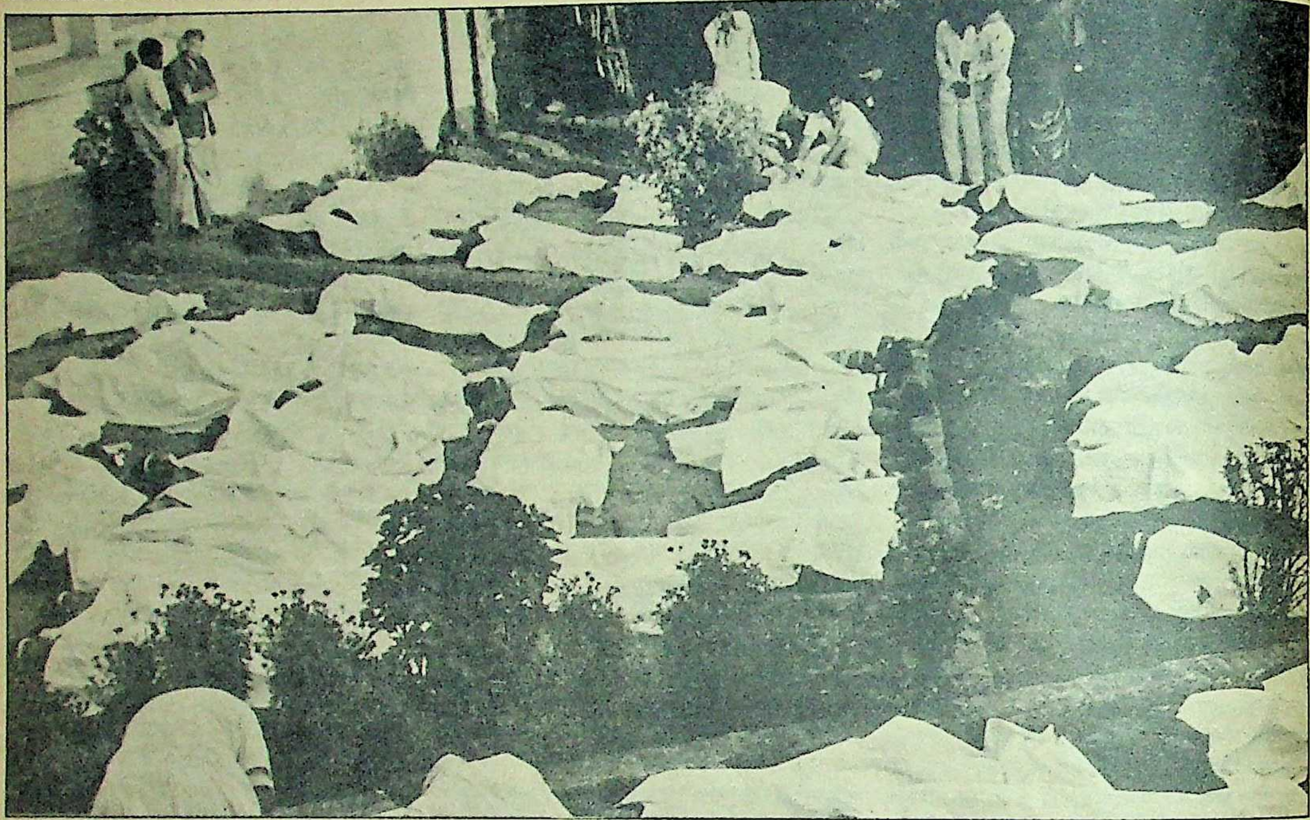

अनमोल प्राणों का सौदा: यूनियन कार्बाइड से रिसी गैस से हुई मौतें

भोपाल गैस कांड

समझौता या सौदा ?

अमरीकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से रिसी जहरीली गैस से जो नरसंहार हुआ था, उसके एवज में भारत सरकार ने अदालत में ३९००० करोड़ रु० के दावे का आवेदन किया था, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि भारत सरकार मात्र ७१५ करोड़ रु० पर ही मान गयी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के सामने घुटने टेक दिये?

१९८४ में दो और तीन दिसंबर की मध्य रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी गैस से जो हादसा हुआ था, उसके मुआवजे का हल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगम यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के मध्य १४ फरवरी को समझौता हुआ कि अमरीकी कंपनी बतौर क्षति पूर्ति ४७ करोड़ डालर (लगभग ७१५ करोड़ रुपए) का भुगतान करेगी।

आशंकाओं और अटकलों के बीच चार बरस से ज्यादा अरसे से हिचकोले खाते माहौल में हुए इस समझौते की भोपाल में तत्काल प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। हालांकि, समझौते की सुगबुगाहट काफी समय से थी, किंतु मुआवजे की राशि को लेकर लोगों के भिन्न-भिन्न अनुमान थे। भारत सरकार ने न्यायालय में दिये गये अपने आवेदन में कहा था कि गैस कांड से हुई क्षति के कुल दावों की राशि ३९००० करोड़ रुपए से अधिक होगी। ऐसे में यदि आवेदन में बतायी गयी राशि को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा किये गये समझौते की रकम का जायजा लिया जाये, तो स्पष्ट होगा कि लाखों गैस पीड़ितों के हिस्से पंचमांश से भी कम राशि आयेगी। इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कितने रुपए आयेंगे, यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता।

समझौता उचित या अनुचित? : समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अब्दुल जब्बार कहते हैं, "भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के सामने घुटने टेक दिये हैं। गैस पीड़ितों से पूछे बगैर सरकार ने उनके बारे में समझौता कर लिया। हजारों लोगों की जान लेनेवालों को पैसा लेकर छोड़ दिया गया। कहां और किस कानून में प्रावधान है कि सामूहिक हत्या के दोषियों को मुआवज़ा लेकर बख्श दिया जाये।" जब्बार भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक हैं। हक की लड़ाई में वे कई बार न्यस्त स्वार्थों के कोपभाजन बन चुके हैं। समझौते के बाद वे करीब दो हजार गैस पीड़ित अभागी औरतों को दिल्ली ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर न्याय की गुहार भी लगा आये हैं। गहरे क्षोभ के बावजूद वे दृढ़ता से कहते हैं, "इस अमानवीय और अनुचित समझौते के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जरूरी हुआ, तो हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटायेंगे।"

इसमें संदेह नहीं कि यूनियन कार्बाइड ने भोपाल के गैस पीड़ितों को कई बार छला है। सुरक्षा और प्रबंध में लापरवाही के बजाय वह दुर्घटना का दोष तोड़फोड़ के मत्थे मढ़ने की कोशिशों में लगी रही है। इसी तरह उसने विषाक्त 'मिक' गैस के दुष्प्रभाव को भी कमतर दर्शाने की कोशिश की है जबकि वास्तविकता यह है कि कार्बाइड के हाथ बहुत लंबे हैं और कार्बाइड लाबी ने सब कुछ सोची समझी चाल के तहत किया है। कहा जा सकता है कि इस खेल में उसने बाजियां हारीं कम, जीतीं ज्यादा।

'मिक' और उसके प्रभावों को ही लें।

'मिक' के विषैले प्रभावों को जानबूझकर कम दर्शाते हुए यूनियन कार्बाइड ने शर्मनाक तरीके से यह प्रचारित किया कि 'मिक' के प्रभाव से केवल फेफड़ों की बीमारी या आक्सीजन की कमी या अधिक अम्लीयता ही हो सकती है। 'मिक' के दुष्प्रभावों पर देश में अनेक संस्थानों के साथ-साथ इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च में भी अनुसंधान चल रहा है जिससे 'मिक' गैस से होने वाले दुष्प्रभावों की असलियत जगजाहिर हो सकती थी। किंतु विडंबना यह है कि संबंधित सूचनाओं पर रोक की हिमायत करके काउंसिल ने यूनियन कार्बाइड की परेशानी को हलका कर दिया है।

सचाई यह है कि यूनियन को 'मिक' के दुष्प्रभावों का पूरा ज्ञान है। उल्लेखनीय है कि फाउलर डाड ने १०.५ व ५.४ पीपीएम 'मिक' से छह घंटों तक प्रभावित 'गिनी सुअरों' के फेफड़ों पर पड़नेवाले गंभीर दुष्प्रभावों के प्रमाण जुटाये थे। 'मिक' श्वसन पर यह अध्ययन जो आज तक सबसे अधिक विस्तृत अध्ययन है, १९८३ में यूनियन कार्बाइड ने निजी तौर पर ठेके पर करवाया था, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ए ३-१२२, १९८१ और ४५-१४४, १९८३ में साफ लिखा है। लेकिन मई '८६ तक इस अध्ययन को दबाये रखा गया। पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में विश्व की सबसे बड़ी व भयावह औद्योगिक दुर्घटना के बाद बेशर्मी से दावा किया कि 'मिक' केवल गले व आंखों में जलन पैदा करती है।

इंडियन टाक्सिकोलाजिकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ की खोजों के अनुसार 'मिक' के असर में आये लोगों पर जीव रासायनिक प्रभाव हुए हैं। 'मिक' न केवल फेफड़ों को कमजोर करती है, वरन रक्त में हीमोग्लोबीन से बंधकर विभिन्न अंगों के एंजाइम तंत्रों में प्रवेश कर जाती है। भोपाल के डा० गोस्वामी के अनुसार 'मिक' क्रोमोजोम में अनियमितताएं पैदा करती है। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के यवेस अलेरी तो कहते हैं, "मिक रक्त में अवशोषित हो जाती है।" अलेरी व ई ब्राउन के शोध इसकी पुष्टि करते हैं कि 'मिक' चयापचयी (पाचन) क्रियाओं को प्रभावित करती है।

नतीजा: उपरोक्त तथ्यों के साये में यूनियन कार्बाइड की गतिविधियों को परखें, तो साफ हो जाता है कि यूनियन कार्बाइड के मालिकों और आकाओं को हजारों लोगों की इस जानलेवा दुर्घटना का खास मलाल कभी नहीं रहा और उनकी यह सतत कोशिश रही कि एक ओर तो वे फौजदारी मामलों के चंगुल से निकल जायें, दूसरी ओर कम-से-कम रकम का भुगतान कर मुआवजे के जंजाल से पिंड छूट जाये। ताकतवर कार्बाइड लाबी ने इस बात की भी पुरजोर कोशिश की कि उसके भारत व विश्व में दूसरे हितों पर आंच न आने पाये। हुआ भी वही जो वे चाहते थे। समझौते और उसके तमाम पहलुओं पर गौर किया जाये, तो यह तथ्य उभरता है कि कार्बाइड लाबी अपने इरादों और मंसूबों में काफी हद तक कामयाब रही है।

अब मुआवजे को लेकर अदालत में चले मामले पर नजर डाली जाये। भोपाल के लाखों गैस पीड़ित जस्टिस देव और उनकी अदालत में हुए फैसले को आज भी याद करते हैं। १७ अगस्त '८७ को यूनियन कार्बाइड ने जस्टिस देव की अदालत में गैस पीड़ितों को ४६ लाख डालर की अंतरिम राहत देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने नगण्य कहकर ठुकरा दिया था। १७ दिसंबर '८७ को जस्टिस देव ने यूनियन कार्बाइड को २७ करोड़ डालर की अंतरिम राहत उपलब्ध कराने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ यूनियन कार्बाइड ने मप्र हाईकोर्ट में अपील की थी। ४ अप्रैल '८८ को मप्र उच्चन्यायालय के न्यायाधीश एसके सेठ ने देव के आदेश का तो अनुमोदन किया, किंतु उन्होंने रकम २७ करोड़ डालर से घटाकर १९.५ करोड़ डालर करते हुए आदेश दिया कि यूनियन कार्बाइड इस रकम का दो माह के भीतर भुगतान कर दे। यूनियन कार्बाइड ने रकम के भुगतान से इनकार करते हुए न केवल उसके विरुद्ध अपील की बात कही, वरन् यह अर्जी भी लगायी कि जस्टिस देव मामले की सुनवाई से अलग हो जायें। इस पर सरकार ने अदालत में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ अदालती अपमान की अर्जी यह कहकर लगायी कि जस्टिस देव को पद व मामले से हटाने के लिए कहना धमकी देने और न्याय को अवरुद्ध करने का सीधा प्रयास है। इसके पूर्व एक दिसंबर '८६ को यूनियन कार्बाइड कोर्ट से वह आदेश रद्द कराने में सफल

> यूनियन कार्बाइड की गतिविधियों को परखें, तो साफ हो जाता है कि यूनियन कार्बाइड के मालिकों और आकाओं को हजारों लोगों की इस जानलेवा दुर्घटना का खास मलाल कभी नहीं रहा और उनकी यह सतत कोशिश रही कि एक ओर तो वे फौजदारी मामलों के चंगुल से निकल जायें, दूसरी ओर कम-से-कम रकम का भुगतान कर मुआवजे के जंजाल से पिंड छूट जाये।

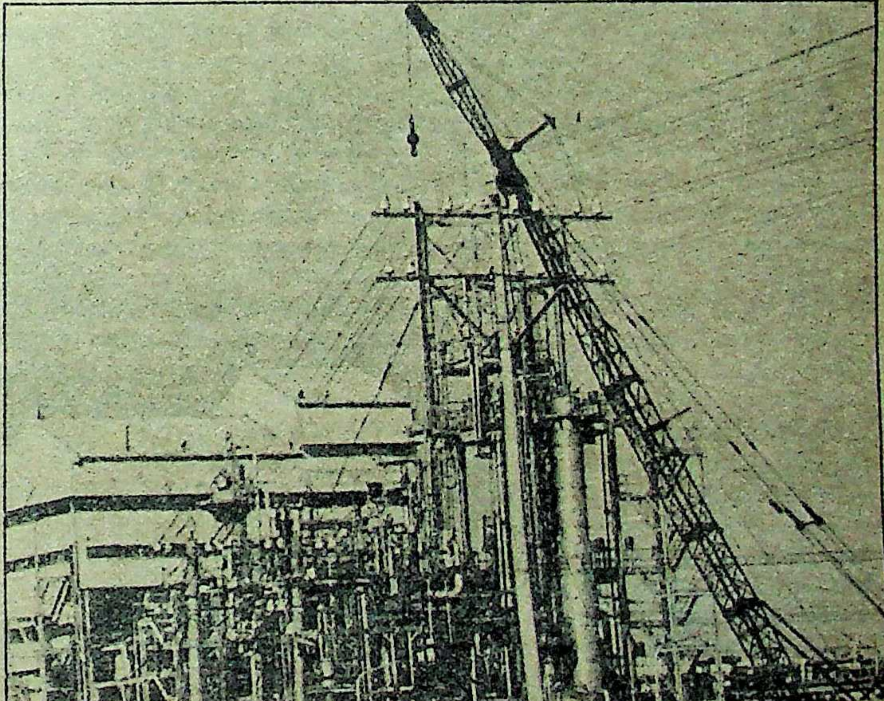

यूनियन कार्बाइड का 'गैस चैंबर'

अपाहिज भविष्य

रही. जिसमें उसे संपत्ति के विक्रय से रोका गया था। अदालत में कार्बाइड ने यह जरूर कहा कि वह अपनी ३०० करोड़ डालर की मुक्त संपत्ति को सुरक्षित रखेगी।

उपर्युक्त संदर्भों से कार्बाइड की नीयत और इरादों का पता चलता है। अगर 'जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड' (न्याय में देरी. न्याय से इनकार है) की सरकारी उक्ति का ही सहारा लिया जाये, तो प्रश्न उठता है कि सरकार ने अगस्त '८७ में कार्बाइड का अंतरिम राहत का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर लिया था? अंततोगत्वा ४७ करोड़ डालर पर हुए समझौते को औचित्यपूर्ण कैसे कहा जा सकता है, नवंबर '८७ में ही कार्बाइड ने १० साल में ५० करोड़ डालर मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा था? इस समझौते की अगर कोई उपलब्धि है, तो बस यही कि ४७ करोड़ डालर एक मुश्त किये गये, अन्यथा मुआवजे के रूप में ५० करोड़ तो पहले ही मिल रहे थे। सवाल यह है कि क्या भीषण गैस त्रासदी की क्षतिपूर्ति के लिए ५० करोड़ डालर काफी हैं?

स्थिति यह है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रघुनंदन स्वरूप पाठक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधानपीठ के समक्ष भारत सरकार के अटार्नी जनरल के पारासरन और कार्बाइड के वकील एफएस नरीमन के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप अब उसके अधिकारियों के खिलाफ दायर आपराधिक मामले भी खारिज माने जायेंगे। अब्दुल जब्बार और अनेक लोग समझौते में मौजूद इस प्रावधान के भी सख्त खिलाफ हैं। उनकी मान्यता है कि हजारों लोगों की हत्या के गुनहगारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती की अध्यक्षता में इंडियन ला इंस्टीट्यूट में हुई बैठक में भी अनेक विधिवेत्ताओं ने समझौते की तीखी निंदा की है। उपेंद्र बख्शी का कहना था कि एक ओर तो कनिष्क विमान दुर्घटना के मृतकों को दस-दस लाख रुपए दिये गये, दूसरी ओर गैस के शिकार मृतकों को दस-दस हजार रुपए देने में भी आनाकानी की जा रही है। बख्शी का कहना था कि देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रबंधकीय और तकनीकी लापरवाही को माफ कर दिया है। राजेंद्र सच्चर इस राशि को इस नाते कम मानते हैं, क्योंकि विशेषज्ञों की राय में 'मिक' गैस से प्रभावित लोगों की दो तीन पीढ़ियां प्रभावित रहेंगी। उनका कहना है कि इस मामले में सरकार और कार्बाइड के अलावा गैस पीड़ितों का भी पक्ष था, जिनकी बात सुनी ही नहीं गयी है।

आशंकाएं : फिलहाल गैस पीड़ितों के मन में मुआवजे को लेकर आशंकाएं कम नहीं हैं। जहरीली 'मिक' गैस की शिकार मतीन मियां की चाल में रहनेवाली बानो बी कहती हैं, "मुआवजा हमें क्या मिलेगा? अफसर और बिचौलिये खा जायेंगे। जो थोड़ा बहुत मिल जाये, तो अल्लाह की मेहरबानी समझो।" बानो अपने पांव पर गैस के प्रभाव से उभर आये चकत्ते दिखाती है। ऐसे ही बदनुमा चकत्ते जहरीली गैस से पीड़ित लाखों लोगों के जिस्म पर उभर आये हैं। कार्बाइड कारखाने के सामने मोहम्मद राशिद की दर्जी की दुकान है। वह तो आज भी समझौते से बेखबर है। हालांकि गैस ने उसकी आंखों और कार्यक्षमता पर असर डाला है। इसी दुकान पर कपड़े काट रहा नौजवान गुस्से में कहता है, "सरकार जान तो क्या नाखून की कीमत भी नहीं दे सकती।" बुधवारा की रशीदा ने पचास हजार मुआवजा मांगा है, परंतु उसे हजार रुपए मिलने की भी उम्मीद नहीं है। यही पीड़ा कमोबेश सभी गैस पीड़ितों की है। पांच बच्चों की मां चंपा देवी को शिकायत है कि सरकार ने गैस पीड़ितों के बच्चों की फीस माफ क्यों नहीं की? अगर फीस माफ होती, तो उसका बेटा परीक्षा दे लेता।

मोतीलाल वोरा के पिछले मुख्यमंत्रित्वकाल में गैस पीड़ितों के लिए काफी योजनाएं बनी थीं और काफी कुछ काम भी हुआ था। उनका ३२२ करोड़ रुपए का एक्शन प्लान तीन साल बीतने के बाद आज भी अधर में है। २२ फरवरी को करीब एक हजार गैस पीड़ितों ने उनसे मुलाकात की। भेंट का हवाला देते हुए उन्होंने 'माया' से कहा, "गैस पीड़ित फैसले से संतुष्ट हैं। अगर दस साल बाद मुआवजा मिलता, तो उसका क्या औचित्य रह जाता?" यह पूछे जाने पर कि क्या प्रदेश सरकार मुआवजे की रकम से अभी तक का खर्च काट लेगी, वे कहते हैं, "अभी तो इसका सवाल नहीं उठता। सर्वोच्च न्यायालय से जो भी निर्देश मिलेंगे, हम उनका पालन करेंगे।" उल्लेखनीय है कि वोरा ने करीब ११ माह प्रदेश से बाहर बिताये हैं। वह इस दरम्यान की घटनाओं के विस्तार में नहीं गये हैं फिर भी कहते हैं, "मैं नहीं समझता कि भारत सरकार व यूनियन कार्बाइड के बीच हुए समझौते में मध्य प्रदेश शासन को अंधेरे में रखा गया है।"

बहरहाल, समझौते के बाद से जिस तरह का माहौल बना है उसे देखकर तो यही लगता है कि इस समझौते के खिलाफ अदालत में और सड़कों पर लड़ाई लड़ी जायेगी। कायदे से मार्च के अंत तक मुआवजे की रकम अदा हो जायेगी। सरकार के लिए और जस्टिस मुले के लिए परेशानियों का दौर इसके बाद शुरू होगा। उन्हें देखना होगा कि मुआवजा वितरण के लिए किस मशीनरी के सहारे कौन-सी प्रक्रिया अपनायी जाये, जिसमें कम-से-कम नुक्स हों। फिलहाल समझौता किसी के लिए लाभप्रद हो या न हो, मगर कार्बाइड के आकाओं के लिए जश्न का बायस तो है ही। वजह यह है कि वे एक तरह से सस्ते छूट गये, फौजदारी मामलों से बच गये और उनकी खड़ी संपत्ति पर आंच नहीं आयेगी। साथ ही उनके एवरेडी सेल जैसे उत्पादन पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ा। जश्न मनाने के लिए ये सारी बातें कम नही हैं।

—सुधीर सक्सेना

धवन की वापसी

राजीव गांधी का आत्मसमर्पण या नयी किलेबंदी ?

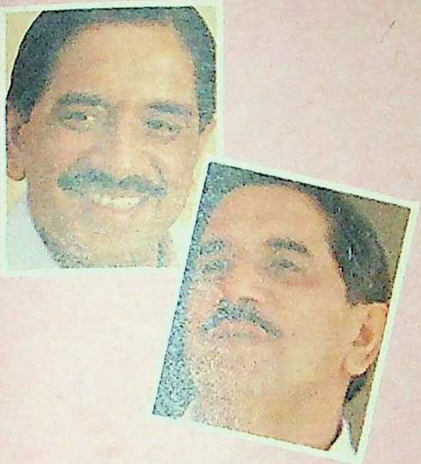

आरके धवन की अप्रत्याशित वापसी क्या इस बात की द्योतक है कि राजीव गांधी ने यह इकबाल कर लिया है कि अब तक उनके सलाहकारों का चयन गलत था? धवन को वापस लाने में किसने भूमिका निभायी है? धवन को क्या काम सौंपा गया है? क्या धवन राजीव गांधी के लिए भी उतने ही उपयोगी और विश्वस्त सिद्ध होंगे, जैसे स्व० इंदिरा गांधी के लिए थे?

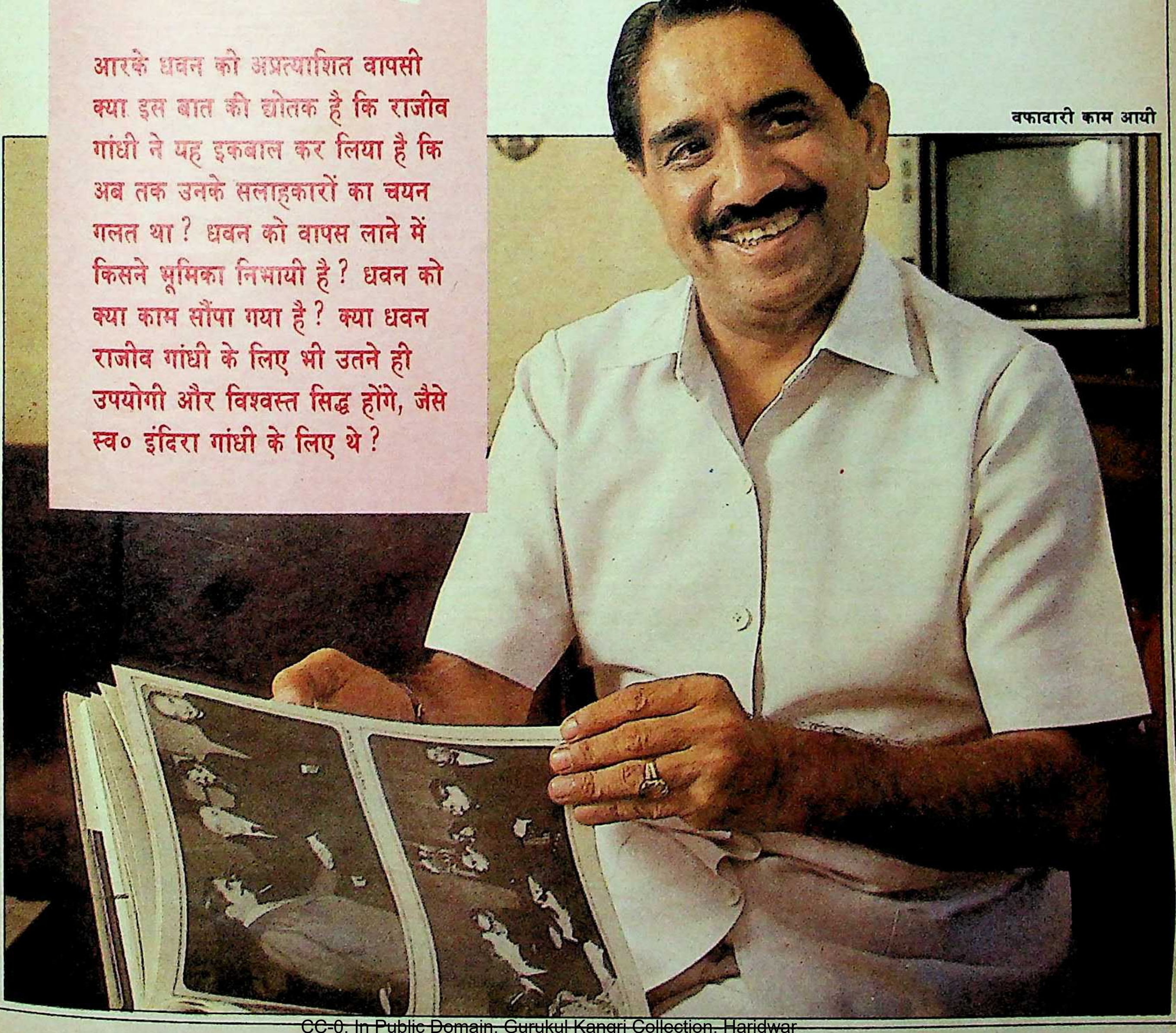

वफादारी काम आयी

शनिवार १८ फरवरी को दूरदर्शन के समाचार कक्ष में रात ८.५० पर टेलीफोन की घंटी यकायक बज उठी। फौरी समाचार राजिंद्र कुमार धवन की कैबिनेट सचिवालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी) पद पर नियुक्ति का था। समाचार विस्फोटक था। कक्ष में हलचल मच जाना स्वाभाविक था। प्रश्न था हिंदी समाचार में इसे उजागर करें अथवा नहीं। अंततः निर्णय हुआ कि इसे अंग्रेजी समाचार में देना अधिक उचित होगा। समूचे देश को उस रात साढ़े नौ बजे के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन द्वारा जानकारी मिली।

मिनटों में धवन के सामने मुस्कानों, बधाइयों, गुलदस्तों और मिठाइयों का अंबार लग गया। देखते-ही-देखते गोल्फ लिंक स्थित उनके निर्जन मकान के इर्द-गिर्द इतनी भीड़ इकट्ठी हो गयी कि नियंत्रण के लिए विशेष पुलिस दस्ते की तैनाती अनिवार्य हो गयी।

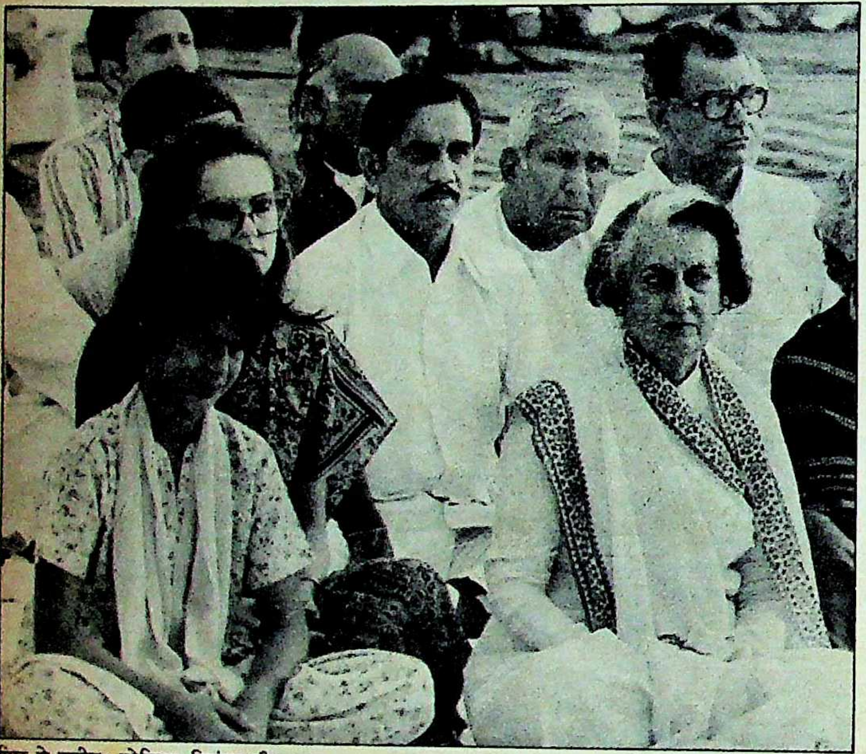

फिर से करीब: सोनिया, प्रियंका और धवन

संकेत: नि:संदेह धवन की वापसी कोई मामूली घटना नहीं। एक पुराने विश्वासपात्र की बहाली के अतिरिक्त इसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी व उनकी पार्टी के अतीत, वर्तमान और भविष्य संबंधी अनेक संकेत निहित हैं। पहला अहम संकेत प्रधानमंत्री की विफलता से उपजी हताशा और आत्मसमर्पण का है। ज्ञात रहे कि ये वही आरके धवन हैं, जिन्हें शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न केवल बुरी तरह अपमानित करके सत्ता गलियारे से निकाला ही गया था, बल्कि जिनके निवास स्थान पर कड़ा पहरा भी बिठा दिया गया था। इसके अतिरिक्त २२ साल तक मां की तरह इंदिरा गांधी को पूजने वाले धवन को इंदिरा गांधी हत्या कांड की जांच के घेरे में लेकर संदिग्ध भी बना दिया गया था। अतिअपमान और प्रताड़ना के पश्चात अब की गयी उनकी बहाली को कुछ ने हथियार डालना ही माना है।

दूसरा महत्वपूर्ण संकेत—नीति और कार्यशैली में अभूतपूर्व परिवर्तन का है। नयी-नयी ताजपोशी और नये जोश के चलते राजीव गांधी ने एक ओर यदि कांग्रेस को सत्ता दलालों से मुक्ति दिला पाक-साफ छवि प्रदान करने का ऐलान किया था, तो दूसरी ओर भारत को अत्याधुनिक तकनीक प्रबंध कौशल से लैस कर २१वीं शताब्दी में प्रवेश दिलाने का दिवास्वप्न भी देखा था। लेकिन साढ़े चार साल में राजीव गांधी को यश के बजाय अपयश अधिक मिला है। इसी का परिणाम है कि वे अपनी मां स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की नीतियों, साथियों को अपनाने के लिए विवश हो गये हैं। राजनीतिक थपेड़ों ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा सबक यही सिखाया है कि सौ वर्ष से अधिक पुरानी कांग्रेस संस्कृति में मूलगामी परिवर्तन का प्रयास आत्मघाती है। चूंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है, इसलिए उसी संस्कृति में रचे-बसे, पारंगत लोगों की बहाली और कार्य शैली अपरिहार्य है। इसीलिए राजीववाद इंदिरावाद के सामने नतमस्तक हो गया है।

तीसरा और कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेत लगभग नौ माह पश्चात अपेक्षित आम चुनाव की बाजी हर कीमत पर जीतने की योजना का है। एक के बाद एक चुनावी हार ने सलाहकारों के सुझावों की खामियों को उजागर करने के साथ-साथ स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वोट बटोरने की क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद ने 'माया' से कहा, "पिछला आम

चुनाव शोकसभा का था। अगला आम चुनाव लोकसभा का होगा।" इसलिए रणक्षेत्र में उतरने के पूर्व तैयारी नये सिरे से करना लाजिमी है।

लडाई कांटे की होगी, यह स्वयं प्रधानमंत्री भी समझ गये हैं। इसीलिए वे एक ओर जहां भोंथरे हथियारों को बाला-ए-ताक रखने को उत्सुक दिखायी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पुराने हथियारों को सान पर चढ़ा रहे हैं। हार की हर संभावना को जीत में बदलने के लिए उन्हें आज दरकिनार किये पत्तों को तुरुप का पत्ता बनाने में राई-रत्ती संकोच नहीं।

विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि धवन की नियुक्ति का फैसला कुछ महीनों पूर्व ले लिया गया था। संपर्क डोर स्थापित थी। फलस्वरूप समय-समय पर धवन की अति विशिष्ट सेवाएं भी लगातार ली जाती रही थीं। किंतु औपचारिक घोषणा के लिए प्रधानमंत्री माकूल मौके की तलाश में थे। कारण वह धर्मसंकट था, कि कहीं गलत समय पर ऐलान कर वे कोई गलत संकेत न दे बैठें।

किंतु इस सावधानी के बावजूद पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह हिचकिचाहट उन्हें दोहरे रूप में भारी पड़ी है। प्रसिद्ध पत्रकार एमजे अकबर जैसों का मानना है कि यदि धवन को हटाया ही न गया होता, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस को इतनी दुश्वारियां न झेलनी पड़तीं। अकबर के अनुसार यदि धवन राजीव गांधी के साथ होते, तो बोफोर्स जैसा कांड या तो उछलता नहीं या इतना विस्फोटक रूप न धारण करता। श्रीमती गांधी के समय में परछाई के समान रहने वाले धवन ने अनेक झंझावातों के दौरान श्रीमती गांधी को सदैव सुरक्षित रखने की अपनी महारत का परिचय दिया था।

श्रीमती गांधी और धवन के बीच कायम तालमेल और कार्यशैली को निकट से जानने वाले एक केन्द्रीय मंत्री ने 'माया' को बताया, "धवन श्रीमती गांधी के लिए एक ऐसे विषपायी थे जो उनके हिस्से के हर दोष को अमृत समान स्वयं ग्रहण कर लेते थे। यदि जनता सरकार अपने तमाम प्रयासों के बावजूद श्रीमती गांधी को कठघरे में खड़ा नहीं कर सकी, तो इसका एकमात्र श्रेय धवन को है। क्योंकि किसी प्रकार के पक्षपात, लेन-देन में श्रीमती गांधी का कभी सीधा हाथ नहीं रहा। उनका 'हर अच्छा-बुरा काम धवन के माध्यम से ही हुआ।

दुर्भाग्यवश राजीव गांधी की सलाहकारों की टोली में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जो उनके लिए ऐसा रक्षाकवच सिद्ध होता। अपने लगभग चार वर्ष से ऊपर के कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी को व्यक्तिगत और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर निरंतर ऐसे सही सलाहकारों की तलाश रही है। किंतु कार्यकाल चाहे अरुण नेहरू, अरुण सिंह, अमिताभ बच्चन का रहा हो अथवा आज के बूटा सिंह, शीला दीक्षित, फोतेदार का, उनकी 'टीम' ऐसी ही रही जो न तो राजनीतिक स्तर पर उनके लिए ढाल बन सकी, न व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें सही सलाह या सूचना ही दे पायी। नतीजतन अनेक विवादों, आरोपों के सीधे घेरे में आने से जैसे-जैसे उनकी अपनी छवि धूमिल होती गयी, वैसे-वैसे जनता और पार्टी पर पकड़ भी कमजोर हुई।

मजबूरी : धवन की वापसी के लिए चुने गये मौजूदा समय ने प्रधानमंत्री की मंजूरी को मजबूरी का स्वरूप प्रदान कर दिया है। विख्यात पत्रकार निखिल चक्रवर्ती की राय है कि 'यह राजीव की शक्ति का नहीं हताशा का परिचायक है।' तमिलनाडु की भारी पराजय और कांग्रेस शासित राज्यों में असंतुष्टों के खुले विद्रोह के ऐन बाद धवन की बहाली को प्रधानमंत्री की हताशा, निराशा से परिपूर्ण अंतिम बाजी अथवा डूबते को तिनके का अंतिम सहारा करार दिया जा रहा है। यह अंतिम बाजी भले ही न हो, किंतु एक सोची-समझी रणनीति अवश्य है, जिसका केन्द्र बिन्दु निश्चित ही धवन हैं। इसी क्रम में धवन-समर्थक उनके गुणों का उल्लेख करते हुए उनकी एकनिष्ठ वफादारी, सुदीर्घ अनुभव, राजनीतिक सूझबूझ और लगभग सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं की—नौकरशाहों की पूरी जानकारी का ब्यौरा देते हैं। इन समर्थकों के

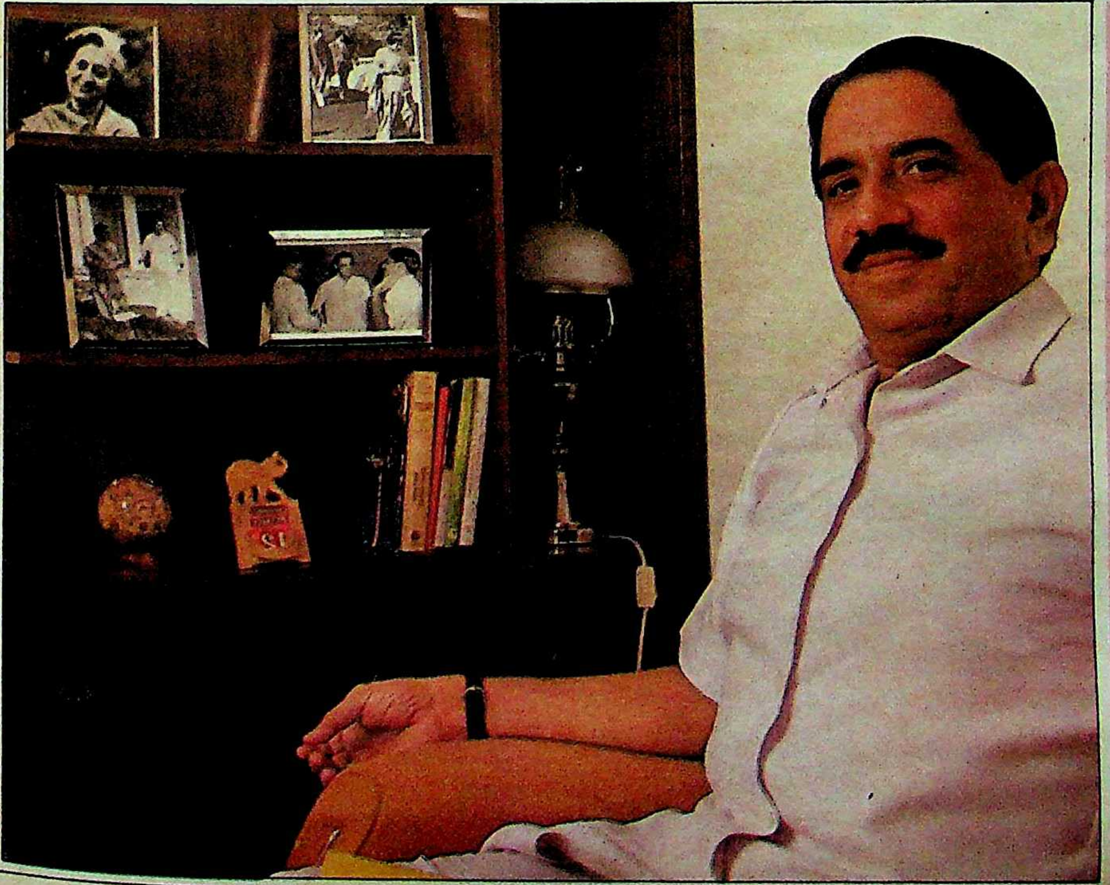

जयपाल रेड्डी ने 'माया' से सवाल किया, "आरके धवन क्या कोई राजनीतिक दार्शनिक, चिंतक अथवा जादूगर हैं, जो उनसे रातो-रात सफलता और मूलगामी परिवर्तन की उम्मीद लगायी गयी है? आज की बदली परिस्थितियों में उनकी सफलता का प्रश्न ही नहीं। विशेषकर इसलिए कि धवन चाहे धवन ही क्यों न हों, पर राजीव गांधी इंदिरा गांधी नहीं हैं।"

अनुसार धवन की बहाली बाजी जिताने में मददगार होगी, किंतु इसके ठीक विपरीत दिलचस्प बात यह है कि स्वयं धवन को आज तक यह मालूम नहीं कि गांधी परिवार की २२-२३ वर्ष तक निरंतर सेवा करने के उपरांत, उन्हें १९८५ में क्यों हटाया गया और क्यों अब उनकी पुनः बहाली की गयी है? वे कोई और नहीं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने उन्हें 'बेहद मेहनत-मशक्कत' करने के बाद 'थोड़ा आराम करने' को कहा था। उन्होंने ही अब उनसे (धवन से) संपर्क कर 'मदद करने' को कहा है।

जहां तक धवन के पद और हैसियत का सवाल है, उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह है कि उनको कैबिनेट सचिवालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का जो पद प्रदान किया गया है, वह उनको सौंपे गये काम का खुलासा नहीं करता है। एक पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी से जब 'माया' ने इस पद का अर्थ जानना चाहा, तो उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, "यह अधिकारी या तो वह होता है, जिसे आप हर हाल में अपनी 'टीम' में लेना चाहते हैं, किंतु उसके लिए कोई उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं होता अथवा उस पद पर उसे सुशोभित किया जाता है, जिसे अपनी टीम में रखना नहीं चाहते, किंतु जिसे बाहर निकालने में असमर्थ हैं।" उपर्युक्त व्याख्या को मद्देनजर रखा जाये, तो धवन पहली श्रेणी में आते हैं।

दूसरा दिलचस्प फर्क यह है कि आधिकारिक घोषणा में कहा गया था कि धवन का कार्यालय राष्ट्रपति भवन में स्थित होगा। किंतु सचाई यह है कि साउथ ब्लाक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में भूतल में पहले से ही तैयार कार्यालय में वे बैठने लगे हैं।

दोनों ही—कार्यक्षेत्र और कार्यालय—में सचाई को ढंकने-मूंदने की जो अजूबी शैली अपनायी गयी है, उससे स्पष्ट है कि उनसे प्रशासनिक कम राजनीतिक काम अधिक लिया-साधा जायेगा। इसकी पुष्टि धवन के ही एक निकट सूत्र जो कि दिल्ली के सत्ता-गलियारे की एक आला हस्ती हैं, ने यह बताकर किया कि धवन को प्राप्त एक पंक्ति के मौखिक आदेश में प्रधानमंत्री ने उनसे वही सारी जिम्मेदारी संभालने को कहा, जो वे स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के समय में संभाला करते थे।

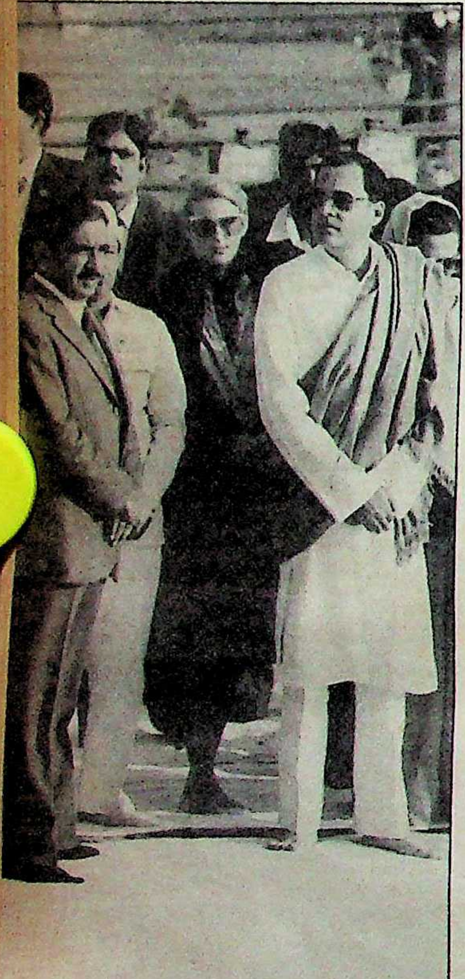

संकट के साथी: राजीव गांधी और आरके धवन

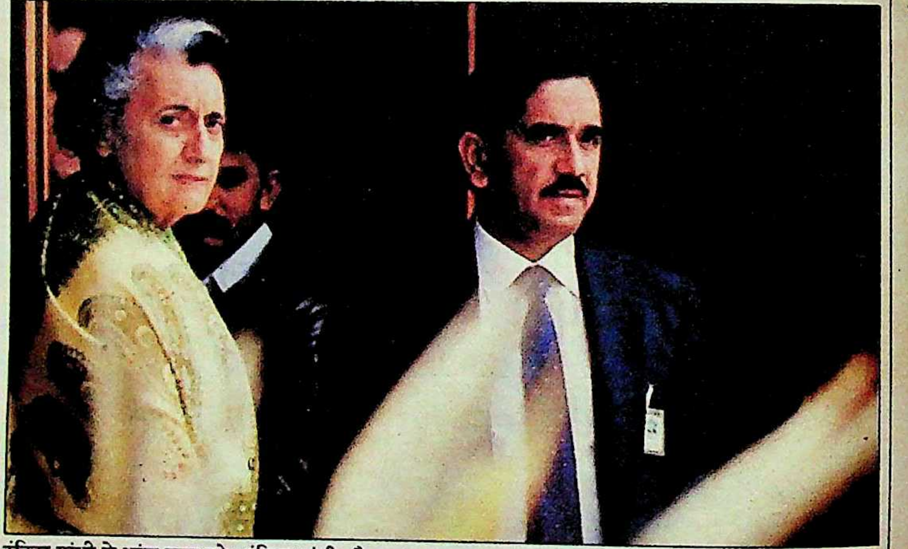

इंदिरा गांधी के आंख-कान रहे : इंदिरा गांधी और धवन

अग्नि परीक्षा : चुनावों को दृष्टि में रखते हुए ही धवन की वापसी हुई है, यह एक जगजाहिर सचाई है। इसके चलते अटकलों-अफवाहों के बाजार में चर्चा गर्म है कि धवन को स्पष्टतया दो काम सौंपे गये हैं—कांग्रेस को जोड़ो और विपक्ष को तोड़ो। और इसी में श्री धवन फिलहाल जुटे बताये जाते हैं? (देखें बाक्स) प्रश्न यह है कि इस कठिन और अभूतपूर्व अग्निपरीक्षा में वे कितने खरे उतरते हैं। विशेषकर इसलिए कि जितना फर्क श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पुत्र राजीव गांधी में हैं, उससे कहीं अधिक फर्क उस समय और वर्तमान समय में है। इस समय जनता अधिक जागरूक—आक्रामक और विकल्प की तलाश में है, शासक दल कांग्रेस बिखराव, विद्रोह और चुनौती की मनोदशा में है और विपक्ष एकजुट हो सत्ता हथियाने के लिए कटिबद्ध है। उन मुट्ठीभर कांग्रेसियों—जो धवन की वापसी से प्रभावित होने वाले हैं या धवन की बर्खास्तगी में जिनका हाथ था—को छोड़कर लगभग सभी कांग्रेसजनों के लिए धवन आशा की एक किरण सिद्ध हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विट्ठल नरहरि गाडगिल ने धवन की बहाली को सही कदम बताते हुए कहा, "अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। श्री धवन को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव प्राप्त है। देश भर के अधिकांश कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं से उनकी निजी पहचान है। कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली और भारतीय शासन प्रणाली का भी उन्हें पर्याप्त ज्ञान है। इसलिए उनकी सेवाएं बहुत उपयोगी होंगी।"

इसके ठीक विपरीत राय व्यक्त करते हुए जनता दल सांसद जयपाल रेड्डी ने 'माया' से सवाल किया, "आरके धवन क्या कोई राजनीतिक दार्शनिक, चिंतक अथवा जादूगर हैं, जो उनसे रातोरात सफलता और मूलगामी परिवर्तन की उम्मीद लगायी गयी है? वैसे धवन की असली भूमिका संदेशवाहक या चौकीदार की ती। ज्यादा से ज्यादा उन्हे बंद कमरे का मैनुपुलेटर कहा जा सकता है। आज की बदली परिस्थितियों में उनकी सफलता का प्रश्न ही नहीं। विशेषकर इसलिए कि धवन चाहे धवन ही क्यों न हों, पर राजीव गांधी इंदिरा गांधी नहीं हैं।"

भिन्न परिवेश : मां-बेटों (श्रीमती गांधी व राजीव गांधी) की सोच-समझदारी, कार्यशैली में काफी अंतर है। अपने पिता स्व० प्रधानमंत्री

जवाहरलाल नेहरू की छत्रछाया में राजनीतिक शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करने वाली श्रीमती गांधी को पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव के अतिरिक्त भारत और जनता जनार्दन की व्यापक पहचान और पकड़ थी। इन सभी में राजीव गांधी उनसे कहीं पीछे हैं। धवन और राजीव गांधी के सोच और शैली में भी फासला काफी है। वर्षों श्रीमती गांधी के साथ काम करने से जहां धवन उनकी हर मुद्रा और मनःस्थिति को भलीभांति समझने लगे थे, वहीं यह भी जानते थे कि कब दो और दो मिलाकर नौ बनाना है, किसे ऊंचा करना है, किसे नीचा। चंद महीनों में राजीव गांधी के साथ उनका ऐसा तालमेल नामुमकिन है। किंतु सबसे बड़ी समस्या विश्वास के प्रश्न को लेकर होगी। श्रीमती गांधी और धवन को एक दूसरे पर जहां शत-प्रतिशत भरोसा था, वहां राजीव गांधी या धवन से इसकी अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं। परस्पर संदेह की दीवार गिराने की कितनी भी कोशिश क्यों न की जाये, उसके निशान मिटाना असंभव है। यही बात अंततः समूची रणनीति की सफलता में बाधक सिद्ध हो सकती है।

संदेह और दुविधा की इसी मनःस्थिति को उजागर करते हुए प्रसिद्ध पर्यवेक्षक कुलदीप नैयर ने एक घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, "धवन के कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति का नोट यद्यपि गत एक फरवरी को तैयार हो गया था, किंतु प्रधानमंत्री ने उस पर अपने हस्ताक्षर १६ फरवरी को ही किये। विलंब का कारण राजीव गांधी की चिरपरिचित टालमटोल की शैली ही नहीं थी, बल्कि धवन द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी की स्वीकृति का विशेष आग्रह भी था। कारण उन्होंने (सोनिया गांधी ने) श्रीमती गांधी के हत्याकांड में धवन की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की थी।"

दिशाहीनता: संदेह श्रीमती गांधी की छोटी बहू और जनता दल नेता मेनका गांधी को भी है—आरके धवन की भावी भूमिका और सफलता को लेकर। मेनका के अनुसार इस वापसी का सर्वाधिक लाभ स्वयं धवन के खाते में जायेगा। कारण, इस बहाली से वे न केवल अपना खोया पद, प्रतिष्ठा वापस पा गये हैं, बल्कि अपने ऊपर लगे दाग को भी काफी हद तक दूर करने में कामयाब हुए हैं। 'माया' से उन्होंने कहा, "धवन के पुनः प्रवेश से कांग्रेस लाभान्वित होगी, ऐसा मैं नहीं मानती। कांग्रेस की मूल समस्या यह है कि उसकी आत्मा मर चुकी है। दुर्भाग्य से राजीव गांधी पार्टी को एक ऐसी मशीन समझते हैं, जिसे कल-पुर्जों की अदला-बदली से कारगर बनाया जा सकता है। किंतु वे कितना भी रद्दोबदल क्यों न करें, पुनः उसे चालू नहीं कर सकते। यदि किसी प्रकार वह एक बार चालू हो भी गयी, तो न तो उसका कोई चालक है न ही कोई दिशा निर्देशक।"

दिशानिर्देश का कितना अधिक अभाव है, यह राष्ट्रपति वेंकटरमण के बजट अधिवेशन के प्रारंभ में दिये गये अभिभाषण से स्पष्ट है। पहली बार

तालमेल में माहिर: इंदिरा गांधी के साथ धवन

पारिवारिक निकटता : धवन गांधी परिवार के साथ

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आगामी वर्ष की सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों के विषय में लगभग मौन धारण कर मात्र गत वर्षों की उपलब्धियों का ही गुणगान किया गया है। भाकपा उपमहासचिव इंद्रजीत गुप्त के अनुसार, "सुनिश्चित नीतियों को तिलांजलि देकर तदर्थवाद के तहत 'संकट आने पर देखा जायेगा' की राजीववाद की जानी पहचानी शैली के अनुसार ही कदाचित ऐसा हुआ है। इन हालात में धवन की पुन: बहाली, राज्यपालों और उच्चप्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल क्या रंग लायेगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है।"

दिशानिर्देश के अभाव के अतिरिक्त इंद्रकुमार गुजराल मौजूदा व्यवस्था में लगे घुन को भी वर्तमान और भावी असफलता का कारण बताते हैं। उनके अनुसार, "लोकतांत्रिक संस्थानों के अवमूल्यन और प्रशासन पर मित्रमंडली के वर्चस्व ने बेड़ा गर्क किया है। आज कैबिनेट मंत्री की तुलना में कोई जूनियर क्लर्क या दोस्त-यार अधिक वजनदार हो जाता है। जब तक व्यवस्था की बहाली नहीं होती, तब तक किसी अन्य की बहाली—भले ही वे आरके धवन क्यों न हों—से कुछ नहीं हो सकता। रोग का निदान ढूंढने और सही दवा-दारू की जगह टोटकों का सहारा लेना अपने को मात्र छलावा देना है।"

चाहे कुछ भी हो, किंतु सचाई यह है कि गत कुछ दिनों से विभिन्न राज्यों के असंतुष्ट कांग्रेसियों की व्यापक गतिविधियों में कुछ ठहराव आया है और अनेक विपक्षी दलों की कांग्रेस और राजीव विरोधी मुहिम अब आपसी विवाद, संघर्ष और मतभेद में परिवर्तित हो गयी है। चाहे यह मात्र संयोग ही क्यों न हो, किंतु दोनों का श्रेय धवन के खाते में डाला जा रहा है। एक जूनियर क्लर्क की हैसियत से मौजूदा बुलंदी पर पहुंचने वाले ५२ वर्षीय आरके धवन के पास सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव के अलावा आम कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं से व्यापक संपर्क-सहयोग की अपनी बहुमूल्य धरोहर है। उनका ज्ञानकोश शासक दल और विपक्ष के नेताओं के समूचे कच्चे चिट्ठे से

साक्षात्कार/कल्पनाथ राय

धवन की सेवाएं लेना मैं ऐतिहासिक आवश्यकता मानता हूं

माया : आपकी दृष्टि में आरके धवन का क्या महत्व है?

राय : क्या हिंदुस्तान में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर एक भी ऐसा व्यक्ति है जो निष्ठापूर्वक २२ वर्ष तक प्रधानमंत्री स्व० श्रीमती गांधी के साथ काम करता रहा हो? धवन का व्यक्तित्व ऐसा फौलादी है कि न तो उन्हें जनता सरकार की जेलें डरा सकीं, न उनके द्वारा दी गयी मंत्रणाएं डिगा सकीं, न सोना धवन को खरीद सका। श्रीमती गांधी के दुर्दिन में जब शाह आयोग और रेड्डी आयोग के सामने सी सुब्रह्मण्यम, एसएसरे, राज बहादुर, एच आर गोखले, टीए पै, रघु रमैया, हरिदेव जोशी, श्रीमती गांधी के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे, उस समय भी श्रीमती गांधी के पक्ष में बोलनेवाले एकमात्र व्यक्ति धवन ही रहे। मुझे १३ अगस्त, १९७७ का वह दिन याद है जब चौ० चरण सिंह ने फोन कर उन्हें नार्थ ब्लाक के अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि इंदिरा गांधी से बड़ा पद ले लो, किसी देश का राजदूत बन जाओ। किंतु जीप केस में मुझे और मेरी सरकार को सही बात बता दो। धवन ने फौरन पेशकश ठुकरा दी। १४ अगस्त को वे कानपुर गये और वहीं चरण सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कराया व उनके पिता को दिल्ली में।

माया : इतने निष्ठावान व्यक्ति को राजीव गांधी ने निकाला क्यों?

राय : श्रीमती गांधी के निधन के बाद श्री धवन ने राष्ट्रपति जैल सिंह से मिलकर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभायी थी। १९८४ के चुनाव जिताने में भी धवन ने तन, मन, धन लगा दिया था। किंतु भाग्य का फेर कि १९८४ के चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने और राजीव गांधी के शपथ लेने के तुरंत बाद ३१ दिसंबर '८४ को राजीव गांधी ने संदेश भेजा कि धवन कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जायें। इसको निजी सम्मान का प्रश्न बनाकर धवन ने तत्काल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को पेश कर दिया। इस प्रकार १ जनवरी '८५ से भारत के दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गये, जब अरुण नेहरू और वीएस त्रिपाठी की चंडालचौकड़ी का एकाधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय में कायम हो गया।

माया : आप जिस चंडालचौकड़ी का उल्लेख कर रहे हैं, उसने ऐसा किस उद्देश्य से किया?

राय : उन्होंने देखा कि १९७७ से ८० तक श्रीमती गांधी के वफादार रहे साथियों पर नियंत्रण करना असंभव है। इसलिए एक ओर इस दौरान श्रीमती गांधी की पीठ में छुरा भोंकनेवाले सत्ता दलालों को अपनी टोली में शामिल करना शुरू कर महत्वपूर्ण ठिकानों पर बिठाना शुरू हुआ, तो दूसरी ओर सभी वफादार साथियों को साम-दाम-दंड भेद के सभी घिनौने हथकंडे से सत्ता ठिकानों से बेदखल करना शुरू कर दिया गया। अरुण नेहरू ने सत्ता के आधे से अधिक ठिकानों पर कब्जा जमा लिया था। अरुण नेहरू को मालूम था कि धवन यदि प्रधानमंत्री सचिवालय में रहे, तो उनका भंडाफोड़ अवश्य करेंगे; इसलिए अपनी चंडाल-चौकड़ी के जरिए साजिश करके उन्हें हटवा दिया।

माया : क्या धवन की वापसी किसी खास उद्देश्य से हुई है?

राय : श्री धवन की सेवाएं वापस लेना मैं ऐतिहासिक आवश्यकता मानता हूं। श्री धवन का लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गहरा संबंध है, नौकरशाही से भी उनका मधुर संबंध है। सत्ता के सभी केन्द्रों के वे अच्छे ज्ञाता हैं। धवन राजीव गांधी के आगामी चुनाव में अवश्य अहम भूमिका निभायेंगे ऐसी मेरी धारणा है। इसलिए देश हित, राजीव हित, कांग्रेस हित को ध्यान में रखते हुए मैंने एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के अपने कर्तव्य को पूरा किया है।

माया : कहा जाता है कि धवन को कांग्रेस जोड़ो और विपक्ष तोड़ो की दोहरी भूमिका सौंपी गयी है?

राय : धवन निश्चय ही कांग्रेस की देशव्यापी एकता स्थापित करने में सफल होंगे। विरोधी दलों से भी उनके संबंध पुराने हैं। श्रीमती गांधी धवन के माध्यम से ही विपक्षी नेताओं की राष्ट्रीय मसलों पर सहमति हासिल करती थीं। पहले वे श्रीमती गांधी के दूत थे। आज वे राजीव गांधी के दूत बनेंगे।

माया : बदली परिस्थितियों में धवन को कितनी कामयाबी मिलेगी?

राय : मैं सब बातें तो नहीं बतला सकता। किंतु विपक्षी दलों के अनेक राष्ट्रीय स्तर के नेता चुनाव के तीन माह पूर्व देश-हित को मद्देनजर रखते हुए राजीव कांग्रेस में शामिल होंगे और देश की एकता-अखण्डता को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। राजीव गांधी का कोई विकल्प नहीं। इसलिए वे विपक्षी नेताओं को कांग्रेस में लाने में अवश्य ही सफल होंगे।

—रंजना कक्कड़

रुतबा : इंदिरा के मंत्रियों के साथ धवन

परिपूर्ण है। मौका पड़ने पर इसका भरपूर उपयोग कर वे सरकार और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का प्रयास जरूर करेंगे। इससे भी अधिक अपेक्षा उनकी व्यापक जनसंपर्क की महारत से की जा रही है। जनसंपर्क द्वारा मन लुभाने और विश्वास जीतने की कला उनमें इतनी अधिक है कि श्रीमती गांधी के कार्यकाल में ऐसी आम धारणा बन गयी थी कि यदि धवन से मिल लिये, तो प्रधानमंत्री (श्रीमती गांधी) से मिल लिये। श्रीमती गांधी का जनता और कांग्रेसजनों से जो व्यापक और सफल जनसंपर्क था, उसमें उनका अपना योगदान तो था ही, धवन भी विशेष उपयोगी सिद्ध हुए थे। धवन के घनिष्ठ मित्र और उनकी वापसी में प्रमुख भूमिका निभाने वाले केन्द्रीय राज्यमंत्री कल्पनाथ राय के अनुसार, "राजनीति, उद्योग-व्यवसाय, प्रशासन एवं जनता—प्रत्येक स्तर पर—धवन का देश व्यापी संपर्क तंत्र फैला हुआ था।"

गलती का अहसास : इसके विपरीत राजीव गांधी के सत्तारूढ़ होने के पश्चात न तो जनता अपने प्रधानमंत्री की भाषा समझ पायी और न प्रधानमंत्री जनता की बोली। नतीजतन दोनों के बीच फासला बढ़ने के साथ-साथ गलतफहमियों में भी इजाफा होने लगा। धवन की बहाली से दो बातें सिद्ध होती हैं। एक, राजीव गांधी को अपनी इस गलती का अहसास हो गया है। दो, धवन के सहारे वे (प्रधानमंत्री) जनता-जनार्दन व कांग्रेस से कड़ी जोड़ने के इच्छुक हैं। धवन से यह अपेक्षा भी है कि वे भारतीय जनता की विनम्रता, सहजता, त्याग, सर्वस्वीकृत मर्यादाओं-मान्यताओं की लक्ष्मण रेखा को पार करने और किसी को 'नानी याद दिलाने', 'जयचंद, मीरजाफर की संतान' करार देने अथवा करुणानिधि के काले चश्मे की खिल्ली उड़ाने जैसे अविवेकपूर्ण कदमों से प्रधानमंत्री को रोकेंगे जो अंततः बहुत भारी साबित हुए हैं।

पारंपरिक और निष्ठावान कांग्रेसियों को धवन की बहाली से भले ही पुराने दिनों और सफलताओं के प्रत्यावर्तन की अपेक्षा क्यों न हो, किंतु प्रख्यात पर्यवेक्षक भवानी सेन गुप्त के अनुसार, "परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि किसी चमत्कार की बात तो दूर, सफलता भी संदिग्ध है। कारण, देश और विशेषकर हिंदीभाषी क्षेत्र में किसी सर्वशक्तिमान सत्ता के आधिपत्य का खातमा हो चुका है। इस क्षेत्र में प्रभुत्व इतने अधिक छोटे-छोटे टुकड़े में विभाजित हो गया है कि इसके अनगिनत क्षत्रप आज किसी प्रकार के आत्मसमर्पण को तैयार नहीं, चाहे इसके लिए पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पांच दूत (बूटा सिंह, फोतेदार, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट व शीला दीक्षित) भेजें या एक (धवन)।"

विपक्षी नेता कतई यह मानने को तैयार नहीं कि धवन की मार्फत उनके किले में सेंध लगायी जा सकती है। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के अनुसार, "अधिक से अधिक वे वामपंथ और गैरवामपंथ में विभाजन का प्रयास कर सकते हैं, जो वे लगातार करते रहे हैं। ताजा उदाहरण संसद में पंजाब मुद्दे पर राजीव गांधी द्वारा मात्र वामपंथ को शहादत का प्रमाणपत्र देने का है। कदाचित वे सोचते हैं कि इससे एक दिन वामपंथ उनका रक्षाकवच बन कर सामने आ जायेगा।" माकपा सांसद सोमनाथ चटर्जी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विपक्ष को विभाजित करने के प्रयास को बचकाना करार देते हुए 'माया' से बोले, "राजीव गांधी न तो 'स्टेट्समैन' हैं न राजनीतिज्ञ और न प्रशासक। चारों तरफ से घिरने पर उन्हें यह भ्रम अवश्य हो गया है कि वे विपक्षी एकता के दुर्ग में सेंध लगा सकते हैं। विपक्ष में विभाजन सिद्धांतों के आधार पर हो, तो हो, प्रधानमंत्री की चुटकुलेबाजी से कदापि नहीं होगा।"

यदि मान भी लिया जाये कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी, व उनके सिपहसालार धवन की मार्फत विपक्षी एकता में विभाजन पैदा करने और असंतुष्ट कांग्रेसजनों को काबू करने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो इससे यह अर्थ कैसे निकाला जा सकता है कि इससे आगामी चुनावों में भी सफलता प्राप्त होगी। समस्या आज कांग्रेस पार्टी की नहीं, उसके नेतृत्व की लुंजपुंज भूमिका की है। पार्टी में व्याप्त विरोध और असंतोष का यही मूल कारण है।

जानकार सूत्रों का दावा है कि धवन की बहाली से प्रधानमंत्री का 'विजय के लिए आत्मसमर्पण' एक बहुत ही सोची-समझी रणनीति के तहत हुआ है। इस रणनीति के अंतर्गत लक्ष्य चुनाव पूर्व के लगभग ६ माह में कांग्रेस का पुनरुद्धार और आम जनता में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि सुधार का है। दोनों महत्वपूर्ण कार्यों का भार जाहिर है, धवन के कंधों पर है। इसी काम में वे इस समय जुटे हैं (देखें बाक्स)।

धवन की रक्षा : धवन के हाथ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कितने उत्सुक थे, यह इसी से स्पष्ट है कि उनकी बहाली की किसी को कानोकान खबर तक नहीं थी। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार धवन की नियुक्ति के बारे में न प्रधानमंत्री के करीबी सलाहकार माखनलाल फोतेदार को पता था और न उनके करीबी गोपी अरोड़ा को। गृहमंत्री बूटे सिंह—जोकि नियुक्ति समिति के सदस्य भी हैं—को इसके बारे में तभी पता चला, जब उनके सामने हस्ताक्षर के लिए फाइल पहुंची। इसे एक रहस्य बनाये रखने का कारण यह था कि प्रधानमंत्री के इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग थे, जो धवन की बर्खास्तगी के षड्यंत्र में शामिल थे और कुछ ऐसे जो अपना महत्व खोने की आशंका से बहाली में बाधक बन सकते थे।

यही नहीं, अब धवन के कामकाज में कोई रोड़ा न अटकाये, इस पर भी प्रधानमंत्री काफी चौकसी बरत रहे हैं। एक जानकार सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नाक की बाल सरला ग्रेवाल को मप्र भेज एक तीर से दो शिकार किये गये। एक तो एक गैरराजनीतिक को राज्यपाल के रूप में वहां भेजकर संतुष्टों-असंतुष्टों दोनों का समर्थन प्राप्त करना था और दूसरे धवन के रास्ते से उन्हें हटाना था। प्रधानमंत्री कार्यालय की वरिष्ठतम अधिकारी श्रीमती ग्रेवाल से धवन का टकराव संभावित था और उन्हें खुलकर काम करने में दिक्कत आ सकती थी।

गोपी अरोड़ा के बारे में भी यही चर्चा है कि उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय में इसलिए लाया गया है, ताकि वे धवन के मार्ग में कोई रोड़ा न अटकायें। इसके विपरीत कुछ जानकार सूत्रों का दावा है कि अरोड़ा के तबादले का मुख्य कारण प्रधानमंत्री राजीव गांधी व वित्तमंत्री एसबी चह्वाण के बीच का कथित मतभेद रहा है। विशेषकर कांग्रेस के 'गरीबी हटाओ अभियान' के लिए आवश्यक धन मुहैया करने के मुद्दे को लेकर। प्रधानमंत्री के लिए इस कठिन समय में इस योजना की तामील से प्राप्त जनसमर्थन और अपनी छवि में सुधार के लिए वामपंथी तेवर वाले गोपी अरोड़ा से उपयुक्त भला और कौन साबित हो सकता था? अन्य तैनातियां भी चुनाव को मद्देनजर रख, कांग्रेस और शीर्षस्थ नेतृत्व की छवि मांजने-चमकाने एवं विपक्षशासित राज्यों के सम्मुख भरसक सांसत खड़ी करने के इरादे का स्पष्ट द्योतक है। प० बंगाल में गुप्तचर विभाग के सर्वेसर्वा रह चुके टीवी राजेश्वर

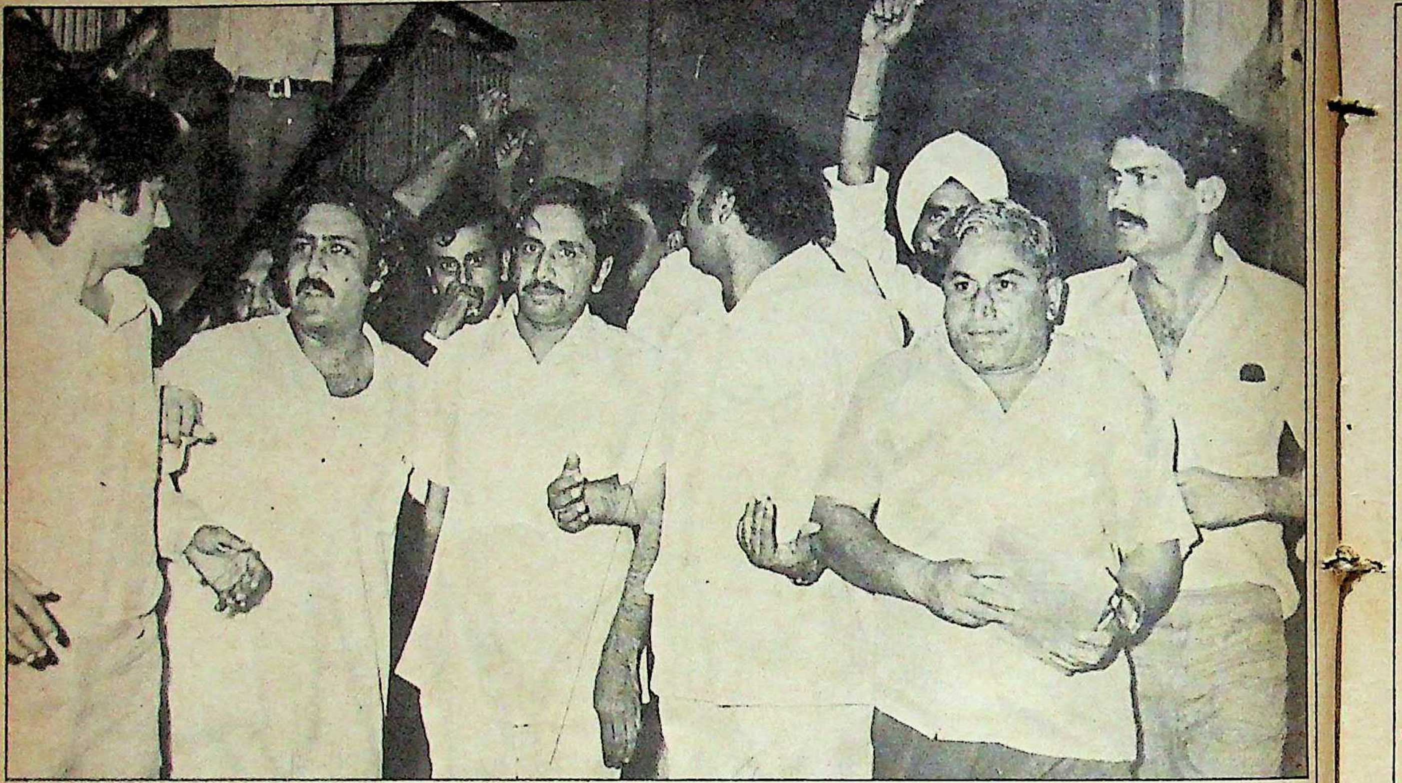

जनता काल में उत्पीड़न: तीस हजारी अदालत के बाहर धवन

को राज्यपाल बनाये जाने के प्रसंग को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ज्योति बसु को पूर्व सूचना तक नहीं दी गयी। गृहमंत्री बूटा सिंह से उन्हें नियुक्ति की सूचना निर्णय के बाद मिली। वैसे सत्ता गलियारे में इस तैनाती ने एक मखौल का रूप धारण कर लिया है, "नूरुल हसन में वामपंथ शासित प० बंगाल को संभालने की 'इंटेलिजेंस' नहीं थी, इसलिए 'इंटेलिजेंस के आदमी' को उनकी जगह भेजा गया।"

जगन्नाथ पहाड़िया को भी बिहार भेजकर एक तीर से दो शिकार किये गये। राजस्थान के संघर्ष के त्रिकोण (शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी व जगन्नाथ पहाड़िया) के एक कोण को राज्य से दूर फेंकने से धवन के लिए जोशी व माथुर में संधि कराने की सहूलियत मुहैया करायी गयी है और गरम राज्य में गोविंद नारायण सिंह जैसे अक्खड़, राज्यपाल की जगह प्रधानमंत्री में 'ईश्वर समान विश्वास' रखने वाले भक्त को भेजकर वहां की आग में पानी डालने की योजना लागू की गयी है। बदलाव के इस दौर में फेरबदल प्रधानमंत्री सचिवालय, केन्द्रीय मंत्रिमंडल और पार्टी संगठन में होने के भी संकेत हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल पीसी अलेक्जेंडर को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में लाने की भी चर्चा गर्म है।

प्रश्न यह है कि धवन को जिस उद्देश्य से लाया गया है, उसमें वह सफल होंगे? उनका मार्ग निष्कंटक किये जाने का कितना भी प्रयास क्यों न किया जाये, किंतु ७, रेसकोर्स में व्याप्त महल की राजनीति से उन्हें अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता। धवन की मदद के लिए जो तंत्र बनाया जा रहा है, उसी में अंतर्विरोध पैदा हो सकता है। खासकर तब जब धवन का प्रभाव क्षेत्र औरों के प्रभाव क्षेत्र पर ग्रहण लगाने लगे। गाज किस-किस पर गिरेगी, इसके बारे में राजधानी के सत्ता गलियारों में पहले से ही चर्चा चल पड़ी है। कोई बूटा सिंह, राजेश पायलट, शीला दीक्षित, पी शिवशंकर व वी जार्ज का नाम लेता है, तो कोई माखनलाल फोतेदार का, जिनका प्रभाव क्षेत्र घटने की बात आज आम हो गयी है। अफवाह यहां तक है कि उनसे कह दिया गया है कि वे अपने इस्पात मंत्रालय का ही कामकाज देखें। ज्यों-ज्यों लोगों के अधिकार-क्षेत्र सीमित होने की संभावना बढ़ती जायेगी, त्यों-त्यों उनका असहयोग और विरोध भी बढ़ता जायेगा।

धवन के कार्य-अधिकार क्षेत्र का खुलासा न होने के कारण उनके संबंध में राजनीतिक-प्रशासनिक हलकों में संशय व भ्रम का विद्यमान होना स्वाभाविक है। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्हें सलाम बजाने वालों की कतार रोजाना बढ़ती जा रही है, तो साथ ही उनके दुर्दिनों में मुंह फेरने वालों की चिंता भी। यश-कीर्ति और महत्ता के अपने शिखर पर क्या धवन पहुंचेंगे? कहा जाता है कि उनका दबदबा ऐसा था कि टेलीफोन पहुंचते ही मुख्यमंत्री अपनी कुरसियों से उठ कर बात किया करते थे। परिस्थितियों में आज जमीन-आसमान का अंतर है। आज जैसी संगीन चुनौतियां पहले कभी दरपेश नहीं थीं। न पहले जैसा राजा रह गया है, न पहले जैसी प्रजा।

धवन की वापसी से कुछ लोग घाटे में होंगे, तो उनके चंद पुराने यारों-पिट्ठुओं का लाभान्वित होना भी स्वाभाविक है। मसलन प्रणब मुखर्जी, गुंडूराव, अंतुले जैसे इंदिरा समर्थकों की ग्रह दशा ठीक हो सकती है। इसी प्रकार लंदन स्थित उद्योगपति स्वराज पाल व बिड़ला के और भी पौबारह हो सकते हैं। घाटे-मुनाफे के इस राजनीतिक खेल का एक अहम प्रश्न यह भी है कि क्या धवन की वापसी से जनता-जनार्दन और देश भी लाभान्वित होगा? शायद इसका जवाब प्रधानमंत्री और स्वयं धवन के पास है, क्योंकि जनता-जनार्दन का फिलहाल भला करने की न कोई नीति उनके पास है न नीयत। 'ट्रायल एंड एरर' के तहत पचीसों बार मंत्रिमंडलीय फेरबदल करने वाले राजीव गांधी आज भी अंधेरे में काली बिल्ली तलाश रहे हैं। चूंकि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, इसलिए धवन का हाथ थामना भी उनकी एक विवशता है। किंतु क्या यह कदम फलदायी होगा? इसका दो-टूक उत्तर दिया—रोहतास (बिहार) के ब्रजकिशोर प्रसाद ने, "जैसे खस्ताहाल परिवार की खुशहाली हवन से संभव नहीं, उसी प्रकार जर्जर कांग्रेस का पुनरुद्धार धवन से संभव नहीं।"

—रंजना कक्कड़,

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

धवन को क्या करना है ?

प्रधानमंत्री की मदद के लिए आरके धवन की वापसी का बुलावा आने के काफी पहले ही उनके 'वनवास' के खतम होने के संकेत मिलने लगे थे। राज्य व्यापार निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर उनके लंगोटिया यार भूपिंदर सिंह की नियुक्ति के समय ही यह शुरुआत हुई थी। सिंह वहां एक निदेशक थे और काफी समय से इस सबसे बड़ी कुरसी के दावेदार थे, लेकिन हर बार धवन की दोस्ती ही उनके आड़े आ जाती थी। सिंह अपनी इस दोस्ती और दोस्त को छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर भी वे अपनी वकालत खुद करने के लिए वाणिज्य मंत्री दिनेश सिंह के पास पहुंचे। उनके दिमाग में पहले से ही कोई आदमी था इसलिए उन्होंने कोई वायदा नहीं किया। खैर इस लंबी कहानी के आखिर में यही हुआ कि एक दिन सुबह जब भूपिंदर सिंह को फोन करके यह बताया गया कि प्रधानमंत्री ने उनके नाम को स्वीकृति दे दी है, तो इस कहानी से जुड़े तीनों ही प्रमुख पात्र अचंभित रह गये। यह पहला संकेत था कि राजिंद्र कुमार धवन का नाम अब राजीव गांधी के लिए उस लाल कपड़े की तरह नहीं रह गया था, जिसे देखते ही सांड़ को गुस्सा आ जाता है।

गोपनीयता : जहां तक धवन की नियुक्ति का सवाल है, यह स्पष्ट है कि राजीव गांधी ने किसी सधे हुए खिलाड़ी की तरह अपने दांव चले हैं। जब यह खबर दूरदर्शन पर आ रही थी, तभी एआईसीसी को भी सूचना दी जा रही थी। सिर्फ बीजी देशमुख को इसकी सूचना पहले से थी, क्योंकि उन्हें ही यह फैसला लागू कराना था। आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि धवन कैबिनेट सचिवालय में 'आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी' न होकर प्रधानमंत्री के लिए 'आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी' हैं, जिनका दर्जा कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव का है। यह एक ऐसा पद है, जिस पर बैठने वाला आदमी देश का सबसे शक्तिशाली नौकरशाह हो सकता है। प्रधानमंत्री के सहयोगी होने के कारण उस दफ्तर से गुजरने वाली हर चीज पर उनकी नजर होगी और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारी होने के नाते सरकार की सभी फाइलों तक उनकी पहुंच होगी।

इसके अलावा, अगर राजीव उन्हें 'राजनीतिक कामों' में लगाते हैं, (जैसा कि आमतौर पर माना जा रहा है) तो उन्हें कोई अधिकृत पद देने की जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से इंका हाईकमान के कामकाज में साउथ ब्लाक जैसे आराम की जरूरत नहीं है। "मैं प्रधानमंत्री की सेवा में हूं," जैसा औपचारिक जवाब देने के अलावा धवन अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ और नहीं बताते, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी नियुक्ति अर्द्ध राजनीतिक है। कुछ राजनीतिक काम, कुछ अधिकारियों वाले काम।

पहली जिम्मेदारी पर पहले गौर करें। धवन के लिए कौन-सी राजनीतिक भूमिका रखी गयी है ? क्या वे फोतेदार की तरह मनमाना व्यवहार करेंगे या बूटा सिंह की तरह आंख मूंद कर ऊपरी आदेश पर चलेंगे ? या फिर वे कोई बेहतर बदलाव लायेंगे ? क्या वे शीला दीक्षित के साथ मिलकर काम करेंगे या उनकी जगह ले लेंगे ? स्पष्ट शब्दों में कहें, तो धवन भी शीला दीक्षित की तरह इंका अध्यक्ष के 'खास' सहायक जैसे ही हैं। अध्यक्ष का काम बहुत बड़ा और जटिल है और उसकी जिम्मेदारियां इन लोगों पर भी आयेंगी, क्योंकि इंका अध्यक्ष ही अभी देश के प्रधानमंत्री भी हैं। शुरुआती खबरों से लगा था कि धवन के सितारे के उदय होने का मतलब शीला दीक्षित के सितारों का अस्त होना है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उनकी काफी अच्छी निभ रही है और सौभाग्य से उनके व्यक्तित्वों की टकराहट जैसी कोई बात नहीं है। बजट वाले पूरे हफ्ते भर वे संसद के निचले तल्ले स्थित बीएस त्रिपाठी के कमरे में शीला दीक्षित के साथ काम करते रहे।

जिम्मेदारियां : राजनीतिक रूप से धवन के लिए तीन मुख्य जिम्मेदारियां तय की गयी हैं: सरकार के कार्यक्रम कितने अच्छे रहे हैं और उन्हें कहां तक लागू किया गया है, पार्टी के बड़े और मझोले नेताओं में किसकी क्या हस्ती है तथा हर राज्य के विक्षुब्धों से कैसे निपटा जाये ?

अपनी दोतरफा रणनीति के तहत धवन ने सबसे पहले विक्षुब्धों का मसला हाथ में लिया और साथ ही संगठन के लिए नयी टीम चुनने का काम भी शुरू किया। अपनी नियुक्ति के पहले उन्होंने बिहार के दिग्गज जगन्नाथ मिश्र से काफी लंबी बात की और उन्होंने सहकारिता 'किंग' तपेश्वर सिंह को भी बातचीत के लिए बुलाया। दोनों ही लोग काफी समय से उन्हें जानते हैं और अखबारों ने जब उन दोनों को राजीव की जगह धवन का आदमी बताया, तो उन्हें काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। इस बात के बाद कुछ समय के लिए ही सही, उन्होंने अपने उग्र तेवर नरम कर दिये और राजीव गांधी को दम भरने का समय मिल गया। मिश्र ने अभी तक कोई उल्टा-सीधा बयान नहीं दिया है, यह बात धवन की समझाने-बुझाने की क्षमता को सिद्ध करती है।

जहां तक कार्यक्रमों के लागू होने और घोषणा पत्र का सवाल है, धवन शायद ही बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में तो सरकार को ही कुछ करना है, पार्टी को नहीं। उनसे कहा गया है कि वे मुख्यमंत्रियों से मिलें, उनसे विवरण लें और राजीव गांधी को बतायें कि इस मामले में अच्छा काम हुआ है या बुरा। लेकिन धवन ऐसा काम करने के अभ्यस्त नहीं हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि २६ फरवरी को जब धवन ने रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री निवास में राजीव गांधी के साथ लंबी बातचीत की थी, तो उन्होंने पार्टी के ढांचे और इसके पदाधिकारियों पर ही अधिक विस्तार से बात की। रिपोर्ट तो यह भी है कि इंका में बड़े पैमाने पर फेरबदल की योजना है। जिला स्तर तक की नियुक्तियों को प्रभावित करने वाले इस फेरबदल से अधिकांश राज्य प्रभावित होंगे। कांग्रेस पार्टी को गतिशील बनाने के लिए जरूरी निचले और मध्यम स्तर के संगठन को पुनर्गठित करने के मामले पर भी धवन शीला दीक्षित के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अवांछित लोगों को अलग रखने और योग्यता को पुरस्कृत करने की अब तक की नीति को एकदम बदल कर अब निष्ठावान लोगों को पुरस्कृत करने की नीति पर चला जा रहा है।

अभी तत्काल भले ही सारा ध्यान राजनीतिक मसलों पर लगा हो, लेकिन धवन की प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी कम मुश्किल पैदा करने वाली नहीं हैं। पार्टी के लिए जिस तरह का काम वे कर रहे हैं, ठीक उसी तरह की आईएएस मशीनरी में उलट-फेर करने की तैयारी भी वे कर रहे हैं। अपनी नियुक्ति के बाद जिन लोगों से धवन ने सबसे पहले संपर्क किया, उनमें प्रधानमंत्री के भूतपूर्व प्रेस सलाहकार एचवाई शारदा प्रसाद भी हैं। धवन ऐसे ही कम शोर शराबे वाले तथा प्रभावी सहयोगियों को चुनना चाहते हैं। लेकिन दूसरा खेमा इन कामों से खुश नहीं है। जैसे मणिशंकर अय्यर धवन की वापसी से खुश नहीं हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, ''चार साल का किया-धरा माटी में मिल गया।''

धवन उम्मीद के अनुसार सारा कुछ कर पायेंगे या नहीं, इस पर विचार करने के पहले दो अन्य बातों पर भी गौर करना चाहिए। मालूम हुआ है कि उन्हें घरेलू गुप्तचर व्यवस्था के कामकाज का मूल्यांकन करने और इसमें बदलाव के बारे में सुझाव देने को कहा गया है। इस फैसले का राजनीतिक और अधिकारियों के अनेक हलकों से भारी विरोध हो रहा है। इस संगठन के काम का तरीका निर्देश देने वालों के मन के अनुसार ही चलने का है। लेकिन सौभाग्य से इस विरोध के बावजूद धवन को अपने बॉस की ओर से अपनी रपट पेश करने के लिए हरी झंडी मिली हुई है। अगर नौकरशाही के ढांचे में फेरबदल के पहले पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था में फेरबदल हो जाये, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

छवि बनाने के लिए : २७ फरवरी को धवन ने शीला दीक्षित, हरिकिशन लाल भगत, सुमन दुबे और कुछ अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री की छवि सुधारने के मामले में लंबी बातचीत की। बातचीत के दौरान टीवी पर जिस तरह से प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है, उस पर टीका-टिप्पणी की गयी। लेकिन जिस तरह से वे एक से मिलने के बाद दूसरे के पास भागते फिरे, उससे लगता है कि इस बातचीत से कुछ खास नतीजा नहीं निकला।

धवन की नियुक्ति में यही सबसे ऋणात्मक बात भी लगती है। १८ महीनों से चौतरफा हमला झेल रही पार्टी और सरकार के लिए धवन ही 'खेवनहार' बनकर आये हैं। उन्हें लाने वालों को लगता है कि बीते दिनों के इस जादूगर के हाथ में अभी भी असर है। लेकिन धवन श्रीमती गांधी के साथ ही बड़े हुए थे और वे उनकी आवाज के एक-एक उतार-चढ़ाव और उनके माथे पर पड़ने वाले हर बल का मतलब जानते थे। आज की राजनीति में इस तरह की समानता को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है।

मौजूदा प्रशासन के लिए भी धवन एकदम अनजान आदमी हैं। व्यवस्था बदल गयी है, नये तौर-तरीके बने हैं और पुरानी परंपराएं टूटी हैं। 'मैडम' के समय वे शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर थे। अब बदलाव वाले माहौल में धवन अगर पहले दस में भी आ जायें, तो उन्हें खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। इसके अलावा धवन इस बात के लिए विख्यात हैं कि वे जो वायदा करते हैं, उसे पूरा करके ही रहते हैं। क्या राजीव उन्हें काम करने की इतनी आजादी देंगे?

राजीव गांधी द्वारा की गयी इस सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। धवन ने बहुत होशियारी से सिर्फ एक ही मांग रखी है : वे सिर्फ राजीव गांधी को ही अपने काम की रपट देंगे और उन्हीं से आदेश लेंगे। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस तरह की अस्तव्यस्तता है, उसमें सिर्फ एक होशियार आदमी ही इस तरह की मांग रख सकता था। दरअसल वहां कौन किसको रिपोर्ट करता है और कौन किसे सलाह देता है, यही न खतम होने वाली बहस का विषय है।

स्पष्ट है कि पुराने चेहरे भी लौटेंगे ही। गुण्डू राव, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल रहमान अंतुले ऐंड कं० का पुनर्वास होगा या नहीं, यह विवाद का विषय है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि चरणजीत सिंह, धीरूभाई अंबानी, राम प्रसाद गोयनका, स्वराज पाल जैसे उद्योगपतियों और कर्नल एसपी वाही, रघु राज, नवीन चावला, एनके सिंह और इन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक दिग्गजों की बड़े धमाके के साथ वापसी होगी। धवन के परिचित लोगों की जो अच्छी जगहों पर हैं, ताकत बढ़ेगी। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर, तमिलनाडु के जीके मूपनार, कर्नाटक के एस बंगरप्पा, उड़ीसा के राम चंद्र रथ, हरियाणा के बंसीलाल जैसे अनेक लोग धवन की वापसी के बाद उनसे मिल चुके हैं।

मौजूदा प्रशासन के लिए भी धवन एकदम अनजान आदमी हैं। व्यवस्था बदल गयी है, नये तौर-तरीके बने हैं और पुरानी परंपराएं टूटी हैं। 'मैडम' के समय वे शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर थे। अब बदलाव वाले माहौल में धवन अगर पहले दस में आ जायें, तो उन्हें खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। इसके अलावा धवन इस बात के लिए विख्यात हैं कि वे जो वायदा करते हैं, उसे पूरा करके ही रहते हैं। क्या राजीव उन्हें काम करने की इतनी आजादी देंगे?

पहली टक्कर : लेकिन राजीव गांधी के लिए लड़ाई शुरू करने से पहले धवन को उन लोगों से निबटना होगा, जिनके अधिकार उन्होंने हथिया लिये हैं। फोतेदार और बूटा सिंह वगैरह भी उन्हें पछाड़ने की ताक में ही बैठे हैं।

कुछ महीने पहले जब जनार्दन रेड्डी को, जो कभी धवन के प्रिय हुआ करते थे, आंध्र इंका का अध्यक्ष बनाया गया, तो एक दिन रेड्डी, बूटा सिंह और कई अन्य कांग्रेसी जार्ज के कमरे में बैठे थे। जार्ज का कमरा संसद में प्रधानमंत्री के दफ्तर से सटा हुआ है। धवन प्रधानमंत्री के चैंबर से निकले और वहां कुछ लोगों से हाथ मिलाने और बतियाने लगे। बूटा सिंह और रेड्डी धवन की आंखों के सामने आने से बचते रहे, लेकिन धवन उन तक आये और कहा, ''बूटा सिंहजी, नमस्ते। रेड्डी हाऊ आर यू? माई नेम इज आरके धवन।''

यह घटना बताती है कि राजीव के दुलारे बने लोग धवन की ओर किस अपमान के भाव से देखते थे। दरअसल यह अटकल भी लगायी जा रही है कि बूटा सिंह जा सकते हैं और धवन इसके लिए कोशिश में लगे हैं। उधर खबर है कि बूटा सिंह धवन के करीबी चरणजीत सिंह के माध्यम से संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। धवन की वापसी से प्रभावित होने वाले एक अन्य व्यक्ति, फोतेदार अभी खामोश बैठे हैं और चालाकी से अपनी गोटी बिठाने की ताक में हैं।

गोपीकृष्ण अरोड़ा ही राजीव के करीबी लोगों में से एकमात्र ऐसे आदमी हैं, जिनका धवन से ठीकठाक संबंध था। यह रिश्ता श्रीमती गांधी के समय का ही है। तब अरोड़ा संयुक्त सचिव थे और धवन अतिरिक्त सचिव। आज भी अरोड़ा की स्थिति धवन के आने से कमजोर होती नहीं लगती। अगर राजीव के काम काज के शुरुआती वर्ष होते, तो अरोड़ा ने धवन की नियुक्ति पर अड़ंगा लगा दिया होता। लेकिन खराब कामकाज वाली टोली के सदस्य होने के कारण अरोड़ा अभी धवन से टकराने की गलती नहीं करेंगे, वरना उनकी 'नौकरी' भी जाती रहेगी। लेकिन धवन अपने तौर-तरीकों और गर्मजोशी के लिए विख्यात रहे हैं। वे इतने दूरदर्शी और चालाक तो हैं ही कि बदला लेने की कार्रवाई पर न उतरें। दरअसल धवन पूरे कांग्रेस रूप महल के लिए एक रहस्यमय 'मसाले' की तरह हैं। अपने सौ साल पूरे करने के बाद कांग्रेस का ढांचा दरक रहा है। चुनाव पूर्व के कुछ महीनों में वे इसे पुरानी शक्ल में तो नहीं ला सकते। लेकिन वे चुनाव तक कांग्रेस को एकजुट करने के लिए 'सीमेंट' तो बन ही सकते हैं। और यदि कांग्रेस चुनाव हर भी जाती है, तो आगे की तैयारी के लिए एकजुट रख सकते हैं।

—के श्रीनिवासन

क्यों निकाला गया था धवन को ?

विश्वसनीय सलाहकार : इंदिरा गांधी और धवन

"अगर वे बहुत चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, तो उन्हें बना दिया जायेगा।" राजिंद्र कुमार धवन ने हंसते हुए यह कथित टिप्पणी १९८३ की जाड़े की एक शाम एक पार्टी में की थी जो इंका सांसद जेके जैन ने स्वराज पाल के अभिनंदन में दी थी। अगले ही दिन सुबह चार सांसद और पार्टी कार्यकर्ता राजीव गांधी के तत्कालीन कार्यालय २-ए, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर धवन की टिप्पणी के खिलाफ विरोध दर्ज करने पहुंचे, जिसका अर्थ उन्होंने यह लगाया था कि धवन अपने आपको इतना शक्तिशाली मानते हैं कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं।

उन दिनों वैसे भी राजीव गांधी के आदमियों—अरुण नेहरू, अरुण सिंह, माखनलाल फोतेदार, विजय धर, विजय शंकर त्रिपाठी— तथा श्रीमती गांधी के चहेतों प्रणब मुखर्जी, राजिंद्र कुमार धवन और स्वराज पाल में एचपी नंदा की एस्कोर्ट्स और भरत राम की दिल्ली क्लाथ मिल को लेकर एक जंग-सी छिड़ी थी। राजीव गांधी के सहायक धवन को एक शातिर व्यक्ति समझते थे, जिसने न्यायपालिका, नौकरशाही, राज्य मंत्रिमंडलों सभी जगह अपने आदमी तैनात कर रखे थे। "हम योजना बना रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को ठीक किया जाये, ताकि वह हमारे क्रांतिकारी कार्यक्रम को सद्भावना से देखे," राजीव के एक सहायक ने एक दिन कहा, "इसी बीच धवन ने चुपचाप अपने दो आदमियों को जज बनवा दिया।" हर बार धवन अपनी चाल से आगे निकल गये और राजीव गांधी के कार्यालय में धवन के प्रति कटुता बढ़ती गयी।

पर २८ फरवरी, १९८३ को २-ए, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर शोक छा गया जब प्रणब मुखर्जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा। राजीव गांधी के सुझाव के विपरीत, मुखर्जी ने अप्रवासी भारतीयों को भारी रियायतें दीं। राजीव के सहायकों ने इसका अर्थ यह लगाया कि मुखर्जी स्वराज पाल की मदद कर रहे हैं, ताकि वे राजीव के तथाकथित दोस्तों की कंपनियों एस्कोर्ट्स और दिल्ली क्लाथ मिल पर कब्जा कर सकें।

जंग तब तेज हो गयी, जब प्रणब मुखर्जी के विशेष सहायक नंद कुमार सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके लिए श्रीमती गांधी को विश्वास दिलाना पड़ा कि सिंह के कारण वित्त मंत्रालय में बैंकों और व्यापारिक संस्थानों को पैसा देने के संबंध में बहुत भेदभाव किया जाता है। राजीव के आदमियों की धवन से लड़ाई में यह पहली जीत थी। स्वराज पाल के भारतीय कंपनियों पर कब्जे को भी रोक दिया गया। धवन के जाने-माने चहेतों, हिंदुस्तान ऐरोनाटिक्स के अध्यक्ष बलजीत कपूर, इलेक्ट्रानिक्स में शांडिल्य भाइयों, एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक रघुराज तथा स्टेट बैंक के अमृत पुरी को या तो नौकरी से निकाल दिया गया अथवा उनकी पदावनति कर दी गयी। तभी एक शाम विजय शंकर त्रिपाठी ने एक विश्वासपात्र से कहा, "लड़ाई जीत ली गयी है, धवन निकाल दिये गये हैं।" अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगभग हो गया था। नंद कुमार सिंह प्रकरण के कारण "श्रीमती गांधी धवन को निकालने के लिए तैयार हो गयी थीं," श्रीमती गांधी के एक भूतपूर्व सहायक का कहना है। उनकी जिम्मेदारियां अरुण नेहरू और विजय शंकर त्रिपाठी संभाल लेते। पर विजय धर, जिनके बारे में आशंका थी कि वह धवन का स्थान लेंगे, संकोची थे, "मैंने बार-बार जोर डाला कि श्रीमती गांधी के प्रति धवन की वफादारी में कोई शक नहीं है। इस कारण उनका खयाल रखना चाहिए।" शायद इसका असर श्रीमती गांधी पर पड़ा। धवन न सिर्फ बरकरार रहे, बल्कि अपना वजन बनाये रखा और श्रीमती गांधी के विश्वासपात्र रहे।

सिर्फ ३१ दिसंबर, १९८४ की देर रात को उन्हें निकल जाने के आदेश दिये गये। प्रधानमंत्री के तत्कालीन विशेष सचिव पीसी अलेक्जेंडर ने धवन को १, सफदरजंग मार्ग पर बुला कर कहा कि सरकार ने श्रीमती गांधी की हत्या की साजिश की तह में जाने का निश्चय किया है और संभव है कि उनसे पूछताछ की जाये। अतः बेहतर होगा कि वे नौकरी छोड़ दें। भारी जनमत से जीत कर अतिप्रसन्न राजीव गांधी वहां उपस्थित थे, पर सिर्फ अलेक्जेंडर का मनोबल बढ़ाने के लिए। उन्हें आशा नहीं थी कि धवन कुछ दिक्कत पैदा कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार धवन छुपी हुई धमकियों और आरोपों से नहीं डरे तथा बीस मिनट तक गुस्से में बहस करते रहे। उनकी दलीलें कुछ हद तक कटु निंदा में बदल गयीं और अलेक्जेंडर अपना हौसला खो बैठे। इसके बाद दलीलें बदली गयीं।

धवन को कहा गया कि उन्हें नये प्रधानमंत्री की नयी टीम बनाने की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में धवन को बता दिया गया कि नये प्रशासन में धवन की कोई जगह नहीं है। बुरी तरह खिन्न धवन १, सफदरजंग मार्ग से आखिरी बार निकले, जहां उन्होंने १६ से १८ साल बिताये थे। उनका निकाला जाना इस बात का प्रतीक माना

गया कि व्यापारियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के कब्जे के विरुद्ध चार साल से चली आ रही लड़ाई जीत ली गयी है। यह भी अर्थ लगाया गया कि श्रीमती गांधीकालीन सत्ता के दलालों का अंत हो गया है, जिनके कारण पार्टी की छवि गिरी तथा राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार पनपा। राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नये युग की शुरूआत के नारे लगे। धवन के मित्र-सहायकों, प्रणव मुखर्जी, कल्पनाथ राय, जगन्नाथ मिश्र, माधव सिंह सोलंकी, विद्याचरण शुक्ल, गुण्डूराव तथा व्यापारी मित्र जैसे स्वराज पाल, चरणजीत सिंह, पीके जैन, तथा नौकरशाह बलजीत कपूर, रघु राज, आर रघुपति आदि पहले ही निकाले जा चुके थे या पदावनत हो चुके थे।

अरुण सिंह ने संसदीय सचिव का काम संभाला, वी जार्ज को साउथ ब्लाक भेज दिया गया। साउथ ब्लाक में धवन के कमरे और आगंतुकों वाले कमरे से लगा वीएस त्रिपाठी का कमरा अरुण सिंह को मिला। त्रिपाठी अगली पंक्ति में स्थित एचवाई शारदा प्रसाद के करीबी कमरे में आ गये। अरुण नेहरू मंत्री हो गये, पर पार्टी प्रबंध के लिए उन्हें यहीं बनाये रखा गया। धवन के अधिकार राजीव के इन खास लोगों में बंट गये।

इस प्रकार १ जनवरी १९८५ से सचमुच एक नये वर्ष की शुरुआत हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी का अंतिम विश्वस्त आदमी भी सत्ता से बाहर कर दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि इससे धवन एकदम बौखला गये, लेकिन तब भी उन्हें आगे आने वाली मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। अनेक गुप्तचर एजेंसियों ने उनसे उस दिन सुबह की बातों के बारे में पूछना शुरू किया, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। इंदिरा गांधी से कुसमय मिलने वालों के बारे में भी पूछताछ की गयी। उन्हें झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने भी बैठना पड़ा। जिस तरह से जांच हो रही थी, उससे यह जाहिर था कि धवन भी संदेह के दायरे से बाहर नहीं थे। इससे वे बहुत मर्माहत हुए। उन्हें लगा कि वीएस त्रिपाठी, अरुण नेहरू और अरुण सिंह ही उनके बारे में ऐसे संदेह पैदा कर रहे हैं। माखनलाल फोतेदार भी इस मंडली में थे। हालांकि अब इस समूह के कुछ लोग कहते हैं, "राजीव की स्वीकृति के बिना हम लोग यह सब कैसे कर सकते थे।"

धवन के एक दोस्त कहते हैं, "चाहे जो हो, धवन ने इस बात का अधिक बुरा माना और वे जनता शासन काल में की गयी पूछताछ से भी अधिक अपमानित महसूस कर रहे थे। वैसे तब उनका दमन अधिक हुआ था।" तब उन्हें बर्फ की सिल्लियों तक पर लिटाया गया था। कहा जाता है कि यह यातना उनको इसलिए दी गयी, क्योंकि उन्होंने चार करोड़ रुपए और विदेश में राजनयिक पद का लालच दिये जाने के बावजूद श्रीमती गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था।

फिर क्या वजह थी जिसने राजीव गांधी को धवन पर संदेह करने को मजबूर किया? यदि धवन को राजीव गांधी के राजनीति में प्रवेश से खतरा होता, कि राजीव के आने से उनकी हैसियत घटेगी, तो वे शुरुआती दौर में ही राजीव गांधी के लिए बाधा बन सकते थे। मजे की बात तो यह है कि जब राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया या जब ८१ के मध्य में वे सांसद बने, तब इस तरह की कोई बात नहीं उठी थी। इस संबंध में संजय गांधी की हादसे में हुई मौत के बाद के दिनों की याद ताजा करते हुए विजयधर बताते हैं कि हालांकि संजय की अचानक मौत ने श्रीमती गांधी को झकझोर कर रख दिया था फिर भी वे काफी हिम्मत से काम ले रही थीं। यही दौर था जब राजीव गांधी को आहिस्ता-आहिस्ता राजनीति में लाने की तैयारी की जा रही थी। धवन यह सब कुछ देख रहे थे, किंतु खामोश थे। सचाई तो यह है कि जब राजीव गांधी को पार्टी सचिव बनाया गया और उनको अधिकार सौंपे गये, तो भी धवन खामोश ही रहे। फिर श्रीमती गांधी को भी इस संबंध में धवन पर कभी संदेह नहीं हुआ। यदि उन्हें ऐसी उम्मीद होती कि धवन राजीव के हितों के विपरीत सोचते हैं या कभी सोचेंगे, तो वे बिना कुछ सोचे-समझे ही धवन के खिलाफ कार्रवाई कर देतीं।

धवन के विरोध के संबंध में आम धारणा यह है कि ऐसा माना जाने लगा था कि धवन के साये में कुछ अपराधी तत्व फल-फूल रहे थे। चूंकि १९८२-८३ में राजीव गांधी पार्टी की सफाई का अभियान चला रहे थे और भ्रष्टाचार उन्मूलन पर जोर दे रहे थे इसलिए हो सकता है उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को धवन का विरोध करने की भी छूट दे दी हो। बाद में धवन की छुट्टी इसलिए कर दी गयी, क्योंकि उनके संबंध जगन्नाथ मिश्र जैसे नेताओं से थे, जो मीडिया तथा जनता की नजर में अच्छे नहीं थे।

धवन विरोधी लाबी में: अरुण नेहरू

अरुण नेहरू मंत्री हो गये, पर पार्टी प्रबंध के लिए उन्हें यहीं बनाये रखा गया।

कहा जाता है कि भागलपुर कांड को लेकर राजीव गांधी ने जगन्नाथ मिश्र को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाये जाने पर जोर दिया था, किंतु धवन ने उनके इस फैसले पर काफी बहस की थी। एक सूत्र का इस संबंध में कहना है, "राजीव गांधी धवन की बहस से काफी चिंतित हो गये थे और १५ दिनों तक उन्होंने किसी राजनीतिक मसले पर श्रीमती गांधी से बात नहीं की थी। बाद में श्रीमती गांधी ने धवन को आदेश दिया था कि वे जगन्नाथ मिश्र को इस्तीफा देने के लिए कहें।"

एक अन्य सूत्र का कहना है कि ३१ दिसंबर, १९८४ की रात में धवन की छुट्टी सिर्फ इसलिए हुई थी, क्योंकि इंदिरा युग का अंत हो चुका था और सत्ता नौजवानों के हाथ मे चली गयी थी। जाहिर है, नये लोगों का काम करने का ढंग काफी अलग-थलग था और उनकी नीतियां और विचार श्रीमती गांधी के सहायकों से मेल नहीं खाते थे। चूंकि लगाम नये लोगों के हाथ में पहुंचते ही श्रीमती गांधी के सहायकों को नजरअंदाज किया जाना शुरू हो गया था, इसलिए धवन के साथ भी वैसा व्यवहार होना लाजिमी था।

इसलिए आरके धवन की वापसी कोई अजूबी बात नहीं है। कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कई बार देखने को मिलता है। श्रीमती गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस में वापस बुला लिया था, जबकि पाटिल ही चिकमंग्लौर के उपचुनाव में श्रीमती गांधी के विरुद्ध लड़े थे। इसी तरह राजीव के समय में प्रणव मुखर्जी और एआर अंतुले की वापसी भी उल्लेखनीय है।

आरके धवन की वापसी की खबर फैलते ही धवन के गोल्फ लिंक निवास पर भारी भीड़ जमा हो गयी। लोग धवन की वापसी की खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि धवन की वापसी के साथ श्रीमती गांधी की नीतियां और कार्यप्रणाली भी किसी हद तक जरूर लौटेंगी। धवन की वापसी इस बात का संकेत है कि राजीव गांधी ने कभी उन पर संदेह नहीं किया था। शुरुआती दौर में विचारों के मेल न खाने की वजह से ही धवन अलग हो गये थे।

पिछले चार वर्षों में परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि राजीव गांधी इस दिशा में सोचने पर मजबूर हो गये कि उन्हें ऐसे सहायक्र की आवश्यकता, है जो श्रीमती गांधी के जमाने के राजनीतिक प्रबंधों से भलीभांति वाकिफ हो। जाहिर है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धवन से बेहतर कौन हो सकता था? क्योंकि धवन राजीव गांधी को यह बता सकते हैं कि जिस तरह की समस्याएं उनके सामने हैं, यदि वे श्रीमती गांधी के सामने पेश आतीं, तो क्या करतीं? **—विजय दत्त**

'द सेटेनिक वर्सेज'

रुश्दी की खता क्या है ?

४१ वर्षीय सलमान रुश्दी के चौथे उपन्यास 'द सेटेनिक वर्सेज' को लेकर अयातुल्ला खुमैनी द्वारा जारी किये गये रुश्दी की हत्या के फरमान ने विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी खेमों में बांट दिया है। आखिर रुश्दी की कल्पना ने ऐसा क्या कहर ढाया है, जिसे लेकर दुनिया में अभूतपूर्व हंगामा मचा है? रुश्दी ने जो कुछ लिखा है वह वाकई कल्पना है या समझी-बूझी साजिश ?

जान के लाले : रुश्दी अपनी विवादास्पद पुस्तक के साथ

बंबई में जन्मे लंदन निवासी ४१ वर्षीय सलमान रुश्दी को उनके चौथे उपन्यास 'द सेटेनिक वर्सेज' ने ब्रिटेन का साहित्यिक बुकर्स पुरस्कार दो बार हासिल करने वाला लेखक तो बना दिया, किंतु उनकी जान के लाले पड़ गये हैं। पिछले लगभग दो महीनों से रुश्दी अपने सनसनीखेज उपन्यास के आपत्तिजनक अंशों की सफाई पेश करते हुए बार-बार यही कह रहे हैं, "मेरे उपन्यास का उद्देश्य किसी धर्म पर उंगली उठाना नहीं। बल्कि उसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है, वह सब मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है।" किंतु आपत्तिजनक अंशों की उनकी व्याख्या किसी के गले नहीं उतरी और देखते-ही-देखते उपन्यास के विरोध में प्रदर्शनों, जुलूसों और दंगों का दौर शुरू हो गया। शुरुआत हुई ब्रिटेन स्थित मुस्लिम विरोध से जिन्होंने पुस्तक को सिरे से इस्लाम विरोधी बताया।

उग्र होता विरोध: आहिस्ता-आहिस्ता पुस्तक के आपत्तिजनक अंशों की खबर पूर्वी देशों तक पहुंची। जाहिर है, मुस्लिम समुदाय, जिसे रोजी-रोटी से ज्यादा अपने धर्म और पैगंबर की इज्जत प्यारी होती है, वह अपने धर्म और पैगंबर के विरोध में लिखे गये उपन्यास को कैसे सहन कर सकता था? नतीजतन माहौल गर्म होने लगा। उपन्यास से बिगड़ रहे माहौल का आभास होते ही भारत सरकार ने रुश्दी की पुस्तक पर पाबंदी लगा दी, जिसे लेकर शुरू के दिनों में लेखकों और बुद्धिजीवियों ने राजीव गांधी के इस कदम की भर्त्सना भी की। बाद में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, मिस्र आदि देशों ने भी रुश्दी की पुस्तक पर पाबंदी लगा दी।

हालांकि मुस्लिम देशों ने पाबंदी लगाकर उपन्यास का विरोध किया था, किंतु थैचर सरकार ने इस खामोश और सांकेतिक विरोध पर ध्यान नहीं दिया। देखते-देखते इस पुस्तक को लेकर ऐसा बावेला खड़ा हुआ कि श्रीनगर और बंबई में दंगे भड़क उठे, जिनमें पंद्रह-सोलह बेगुनाह लोगों की जानें गयीं और सैकड़ों जख्मी हुए। इस्लामाबाद में अमरीकी सांस्कृतिक केंद्र के सामने 'सेटेनिक वर्सेज' के विरोध में प्रदर्शन कर रहे इस्लाम के दीवानों को तितर-बितर करने के लिए जब पुलिस ने आंसू-गैस का इस्तेमाल किया, तो प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पलक झपकते ही छह लोगों की जान चली गयी और संघर्ष में सैकड़ों लोग घायल हो गये। जब रुश्दी को इस तरह की घटनाओं की सूचना मिली, तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा, "मैंने तो ऐसी कोई पुस्तक नही लिखी जो लोगों की जिंदगी की प्यासी हो या जिसको लेकर विवाद खड़ा किया जाये।" यह बयान देते समय रुश्दी यह भूल गये थे कि मुसलमान अपने धर्म के बारे में इतना कट्टर होता है कि इस्लाम, कुरान या पैगंबर का मजाक उड़ाना तो दरकिनार, यदि पैगंबर का नाम भी मजाक के लहजे में लिया जाये, तो वह सहन नहीं कर पाता।

विरोध का चरमोत्कर्ष: प्रदर्शनों, जुलूसों, सभाओं और दंगों का दौर रुक-रुककर चल ही रहा था कि ईरान के ८८ वर्षीय आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी ने अपना फतवा जारी करके आग में घी डालने का काम किया। खुमैनी ने अपने फतवे में साफ कहा, "चूंकि सलमान रुश्दी ने अपने उपन्यास में इस्लाम, कुरान और पैगंबर का मजाक उड़ाकर उनकी तौहीन की है, इसलिए बतौर सजा उनको कत्ल किया जाना चाहिए।" खुमैनी के इस ऐलान की देर थी कि रुश्दी-विरोधी मुहिम ने गति पकड़ ली। समाचार-पत्रों में रुश्दी संबंधी समाचारों का अंबार लग गया। कोई लिखता ईरान के आतंकवादी दस्ते रुश्दी की हत्या के लिए ब्रिटेन रवाना हो गये हैं, तो कोई खबर देता कि ब्रिटेन में ही प्रशिक्षण पा रहे आतंकवादी दस्तों ने रुश्दी की खोज शुरू कर दी है। मौत का ऐलान सुनते ही रुश्दी ने उत्तरी लंदन स्थित अपना चार मंजिला मकान छोड़ दिया था और स्काटलैंड यार्ड के आतंकवाद विरोधी दस्तों की सुरक्षा में कहीं जा छिपे थे। रुश्दी को पूरा यकीन हो आया था कि पूर्वी देशों में उनके उपन्यास को लेकर जिस तरह का बावेला उठ खड़ा हुआ था, उसका अंजाम बुरा ही है। फिर अयातुल्ला खुमैनी का फैसला हवा में नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि इसमे पहले भी खुमैनी इस तरह का फतवा जारी कर चुके थे, जिसका अंजाम सबको पता था।

पश्चिमी देशों का रवैया: ईरान द्वारा मौत का आदेश जारी किये जाने के बाद मारने वाले को २६ लाख डालर (गैर ईरानी को १० लाख) के ईनाम की घोषणा भी की गयी। ईरान ने ब्रिटिश

ईरान के अंदर

फतवे की ओट में

इस्लाम का अपमान असह्य : खुमैनी

माफ नहीं किया : रुश्दी

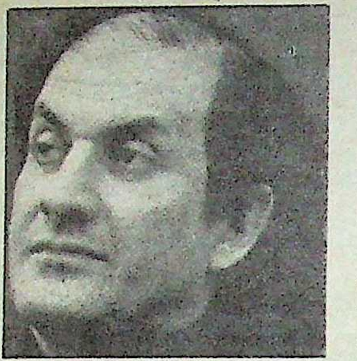

अनेक मौलवियों का मानना है कि खुमैनी का इस्लाम, मोहम्मद साहब के उपदेशों से काफी अलग लगता है। लेकिन ये लोग भी खुमैनी के अदृश्य लंबे हाथों से डरे हुए हैं। वे बताते हैं कि खुमैनी के अनुसार, "इस्लाम कहता है : सभी काफिरों को खतम कर दो, उन्हें तलवार से खतम कर दो।"

ऐसे में सलमान रुश्दी के खिलाफ उन्होंने जो फतवा जारी किया है, उसे खुमैनी के जानने वालों ने 'सामान्य' ही कहा है। लेकिन दुनिया भर के लोगों की सबसे अधिक चिंता इस बात को लेकर है कि इस फतवे के दूरगामी परिणाम क्या होंगे और इससे लोगों की जीवन-पद्धति पर इस्लामी कठमुल्लेपन की पकड़ कितनी बढ़ जायेगी।

दरअसल इस विकराल नाटक में रुश्दी की अब कोई भूमिका ही नहीं रह गयी है। अब तो सबकी निगाहें इस नाटक के नवीनतम दृश्य के अभिनेताओं की गतिविधियों को देखने के लिए तेहरान पर लगी हैं। किसी को भी पता नहीं कि कहानी किस पल क्या मोड़ ले लेगी?

अभी कोई यह भी नहीं कह सकता कि कठमुल्लों और राजनेताओं के जेहाद में आखिरकार कौन जीतेगा। अब तक तो प्रगतिशील माने जानेवाले ईरानी संसद के अध्यक्ष अली अकबर हाशमी रफसनजानी और विदेशमंत्री अली अकबर विलायती का पलड़ा भारी है और उसका श्रेय रुश्दी के माफीनामे को दिया जाना चाहिए। अभी तो चोट खाकर अपने मौके की प्रतीक्षा में बैठे हैं प्रधानमंत्री मीर हुसैन मुसावी, गृहमंत्री अली अकबर मोहतशमी और अयातुल्ला खुमैनी के पुत्र अहमद खुमैनी, जिनके आसपास सत्ता केंद्रित है।

सत्ता-संघर्ष : इन सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य है सत्ता। पिछले अनेक महीनों से ये सभी लोग अपनी छवि सुधारने और अधिक महत्व हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। संयोग से रुश्दी इसी बीच आ गये। वे इस तेज चालवाली शतरंज के दांव का एक मोहरा बन गये। तेहरान से तो अभी यही छवि उभरती है कि अयातुल्ला खुमैनी ने फतवा जारी किया है कि अपनी किताब 'सेटेनिक वर्सेज' में इस्लाम की निंदा करनेवाले रुश्दी को खतम कर दिया जाये और उनके इस फतवे पर दुनिया भर में काफी गुस्से एवं नाराजगी का इजहार हुआ है।

खुमैनी ने पहली बार किसी लेखक की हत्या करने का फतवा नहीं दिया है। १९४६ में ईरानी इतिहासकार अहमद कसरावी और उनके सचिव की हत्या एक नौजवान हसन इमामी ने कर दी थी। वे शियाबहुल ईरान में अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इस हत्याकांड में खुमैनी के सीधे शामिल होने का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से वे कसरावी को धमकाते रहे थे उससे हर आदमी को यकीन हो गया था कि वे भी इस हत्या से जुड़े थे। कसरावी की हत्या के आसपास खुमैनी ने अपनी किताब कास्क-अल-अशर (रहस्यों का खुलासा) में इतिहासकार की ओर इशारा करते हुए लिखा, "मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे नापाक तत्वों को पृथ्वी से हटा दें।"

खुमैनी की दूसरी किताब 'वाइज अल आसेल' भी इस्लाम और मोहम्मद साहब का अपमान करनेवालों के बारे में उनकी सोच बताती है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर किसी ने मोहम्मद साहब का या इस्लाम का अपमान किया है, तो उस आदमी की हत्या न करनेवाले मुसलमान को पाप लगेगा। अयातुल्ला की बेटी जोहरा मुस्तफवी ने हाल में वाशिंगटन टाइम्स को दिये इंटरव्यू में खुमैनी के मन के बारे में बहुत स्पष्ट विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता इस्लाम के किसी भी अपमान को बरदाश्त नहीं कर सकते और ऐसा होने पर वे परिणाम की चिंता किये बिना एकदम अतिवादी तरीके से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। जोहरा ने इंटरव्यू में ही उनके कुछ वाक्य उद्धृत किये, "अगर मेरी प्रतिष्ठा गिरती है, तो गिरे। मुझे सिर्फ इस्लाम की रक्षा की परवाह है, अपनी नहीं।"

कसरावी की हत्या के समय भले ही अयातुल्ला का वर्चस्व था, लेकिन अब यह शक किया जा रहा कि रुश्दी की हत्यावाले फतवे पर उनसे जबरन दबाव डालकर 'हां' करा ली गयी है। ऐसा करानेवालों में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और खुमैनी के बेटे जैसे लोग हैं, जो तेहरान की सत्ता की लड़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं।

इन तीनों की राजनीतिक सत्ता उसी दिन से क्षीण होने लगी थी, जब लड़ाई में हार का अंदेशा देखकर बुद्धिमान रफसनजानी ने खुमैनी को खाड़ी युद्ध समाप्त करने के लिए राजी करा लिया था। ईरान की अंतिम जीत होने तक लड़ाई चलाते रहने की वकालत करनेवाले मुसावी वगैरह तब से रफसनजानी को दरकिनार करने की कोशिश में लगे थे और सात महीने बाद उन्हें एक अच्छा मौका हाथ लगा।

असली निशाना : असली निशाना रुश्दी नहीं थे। उनकी बंदूकें अली अकबर हाशमी रफसनजानी की ओर तनी थीं, जिनकी मध्यमार्गी विदेशनीति भी उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। वे पश्चिमी देशों के साथ ईरान के बढ़ते संपर्क के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे वहां यूरोपीय पूंजी, कंपनियां आयेंगी और ईरान में पश्चिमी आर्थिक सत्ता फिर जमेगी। उनका मानना है कि इससे ईरान की इस्लामी क्रांति की शुद्धता जाती रहेगी।

रफसनजानी और उनके मुख्य समर्थक, विदेशमंत्री विलायती जब पश्चिम से दोस्ती की कोशिशों के लिए वहां गये, तो मुसावी और मोहतशमी ने पश्चिम से बढ़ते ईरानी संबंधों को तोड़ने की अनेक योजनाएं बना लीं। इसी वक्त रुश्दी की 'सेटेनिक वर्सेज' भी आ गयी। उनकी रणनीति बन गयी : खुमैनी को भी इस फंदे में घेर लेना। इसके बाद एकदम दुबले-पतले और अलग-थलग रहने वाले ८८ वर्षीय अयातुल्ला खुमैनी, जो अब सही-गलत का भेद कर पाने की स्थिति में भी नहीं रह गये हैं, के नाम से रुश्दी की हत्या का फतवा जारी हुआ।

मुसावी और उनकी मंडली की रणनीति कुछ हद तक सफल भी रही। करीब-करीब सभी पश्चिमी देशों ने खुमैनी के फतवे की निंदा की। हालैंड के विदेशमंत्री ने अपनी तेहरान यात्रा रद्द कर दी। फ्रांस के राजदूत कुछ विचार-विमर्श के लिए पेरिस आये थे, उन्हें वहीं अनिश्चितकाल के लिए रोक लिया गया। ब्रिटेन, जिसने हाल में ईरान के साथ राजनयिक संबंध फिर से शुरू किये थे, ने फ्रांस और कनाडा के साथ तेहरान में अपने राजनयिकों की संख्या न बढ़ाने का फैसला किया। यूरोपीय समुदाय ने भी ऐसा ही किया। ऐसा लगता है कि ईरान एक बार फिर पूरी दुनिया से अलग-थलग पड़ जाने की स्थिति में पहुंच गया है।

अपने विरोधियों द्वारा किये गये नुकसान का अहसास करते ही निर्भय रफसनजानी तेजी से सक्रिय हुए। उन्होंने राष्ट्रपति अली खमेनी से एक बयान दिलवाया कि अगर रुश्दी अपनी गलती मानकर मुसलमानों और इमाम (खुमैनी) से माफी मांगें, तो उन्हें माफ कर दिया जायेगा। कट्टरवादियों में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रुश्दी झुक जायेंगे और जब रुश्दी झुक गये, तो इन गरमपंथियों का खेल खतम हो गया। यह काम करने के साथ ही रफसनजानी ने तेहरान के अखबार 'इत्तेलात' के माध्यम से भी कठमुल्लों पर एक हमला कराया। अखबार ने हत्या के आदेश की निन्दा की और रुश्दी के सिर पर इनाम रखने को 'किसी माफिया गिरोह जैसा काम बताया, न किसी संत या धार्मिक आदमी का।' तुरंत अंग्रेजी के अखबार 'काहयान

इंटरनेशनल' ने भी इसी विचार का समर्थन कर दिया।

सूत्रों का कहना है कि बीमार और एकदम महत्वहीन हो गये खुमैनी को अपने इर्द-गिर्द चलने वाले सत्ता-संघर्ष का ठीक-ठीक पता भी नहीं है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता, तो अखबारों में उनको धार्मिक नेता के रूप में चुनौती दिलवानेवाले रफसनजानी का एक दिन जीना भी दूभर हो जाता।

रुश्दी और उनकी किताब पर उग्र रूप अपनानेवाले गरमपंथियों के दिमाग में कुछ और ही उद्देश्य हैं। १९८७ में हज के वक्त मक्का में उपद्रव कराने पर मुस्लिम दुनिया द्वारा की गयी निंदा और खाड़ी युद्ध में पराजय का अपमान झेलने के बाद अब वे लोग खुमैनी पर फिर से अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। रुश्दी को वे लोग इस्लाम के बारे में गलत-सलत प्रचार करनेवाला और पश्चिमी प्रेस का दलाल मानते हैं और उनकी छवि पर हमला करके वे लोग अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उनका दांव शुरू में ही उल्टा पड़ गया, जब मध्य-पूर्व के बुद्धिजीवियों और विद्वानो ने रुश्दी की किताब से असहमति जताते हुए भी खुमैनी की इस बात के लिए निंदा की कि उन्होंने इस्लाम की सहनशीलता की शिक्षा पर अमल नहीं किया।

मिस्र के नोबल पुरस्कार विजेता साहित्यकार, जिनकी किताब 'द चिल्ड्रेन आफ गेबलवी' को धर्मविरोधी बताकर ३० साल पहले मिस्र में प्रतिबंधित कर दिया गया था, ने कहा, "जिस नेता ने ऐसा फैसला दिया है, उसे सजा मिलनी चाहिए, भले ही इस पर अमल हुआ हो या नहीं। हत्या अपराध है, तो हत्या के लिए उकसाना भी उतना ही बड़ा अपराध है। हत्या का खयाल ही गलत है। मैं खुमैनी के फतवे को इस्लाम और मुसलमानों पर ही आक्रमण मानता हूं।"

प्रमुख इस्लामी विद्वानों ने मौत के फरमान की निंदा करने में कोई कोताही नहीं की। त्रिपोली स्थित लीबिया के इस्लामी कालेज के प्रमुख ने कहा कि रुश्दी की हत्या के फतवे से मुसलमान गैरमुस्लिम दुनिया को धर्मांध और रक्तपिपासु दिखने लगे हैं। ऐसी कार्रवाई की जगह उन्होंने किताब में छपी बातों का वैज्ञानिक ढंग से जवाब देने की वकालत की। ट्यूनिशिया के बड़े मुफ्ती शेख मुख्तार 'सेटेनिक वर्सेज' को धर्म पर आक्षेप करनेवाला तो मानते हैं, लेकिन वे भी खुमैनी के फतवे का समर्थन नहीं कर सके।

दुनिया का आध्यात्मिक प्रमुख बनने का खुमैनी का सपना अब पूरा नहीं हो सकता। रुश्दी प्रकरण ने उनकी पोल खोल दी है और उनके गरमपंथी समर्थक भी अपना उद्देश्य पूरा करने की स्थिति में नहीं रह गये। अरब लीग के पदाधिकारी हामिद एसिद के शब्दों में, "खुमैनी न तो इस्लाम के प्रतिनिधि हैं, न शिया मत के।" और अब यह बात अधिकांश मुसलमानों को सही लगती है।

—जॉय राफेल, रियाद से

सरकार से इस बात की सफाई पेश करने का भी आग्रह किया कि उसने ऐसी पुस्तक के प्रकाशन पर पाबंदी क्यों नहीं लगायी, जिसमें किसी धर्म विशेष को निशाना बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिये जाने पर ईरान के कट्टरपंथी आगबबूला हो उठे और तीन माह पहले ही तेहरान में खुले ब्रिटिश दूतावास पर टूट पड़े। दूतावास पर हमला होते ही थैचर सरकार के कान खड़े हो गये। अब तक हीलाहवाली करके बात टाल रही सरकार को अब इस बात का अंदाज हुआ था कि मुस्लिम कट्टरपंथी रुश्दी के उपन्यास 'द सेटेनिक वर्सेज' से बेहद खफा हैं। फिर भी सरकार ने रुश्दी या उनकी पुस्तक के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, किंतु ईरान के आक्रामक रवैये की निंदा करते हुए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता की मांग की। देखते-देखते पश्चिमी देशों में ईरानी रवैये को लेकर खलबली मच गयी और एक के बाद एक ईरान विरोधी बयान जारी किये जाने लगे। कोई ईरान के नजरिये को पिछड़ा हुआ बताता, तो कोई खुमैनी के फतवे की भर्त्सना करता। लगभग सभी पश्चिमी देश इस बात पर एकमत थे कि लिखने और बोलने की स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं लगायी जा सकती। ईरान को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। किंतु ईरान भी मानने को तैयार नहीं था। जाहिर है, जिस खुमैनी की जिद ने आठ साल तक जारी रहे खाड़ी युद्ध में लाखों बच्चों, औरतों और मर्दों की जान की परवाह नहीं की, उसे आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों की चेतावनी की परवाह कैसे होती? ईरान ने अपना अड़ियल रवैय बरकरार रखा और आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों से अपने दूत वापस बुलाने शुरू कर दिये। यही नहीं, ईरानी मजलिस (संसद) में ब्रिटेन से राजनयिक संबंध समाप्त करने का बिल भी पेश किया गया, जो पहले चरण में पारित हो गया। यही नहीं, हाल में ईरानी कट्टरपंथियों ने 'द सेटेनिक वर्सेज' का उर्दू में अनुवाद कर रहे स्वीडिश नागरिक को भी जान से मारने की धमकी दी है तथा 'सेटेनिक वर्सेज' के प्रकाशक वाइकिंग पेंग्विन के लंदन तथा न्यूयार्क स्थित कार्यालयों पर भी हमले का ऐलान किया है। न्यूयार्क स्थित पेंग्विन कार्यालय के समक्ष अमरीकी मुसलमानों ने प्रदर्शन कर पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप किया, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गयी। अमरीका में भी माहौल बिगड़ने का आभास होते ही अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने ईरान के फैसले की भर्त्सना की तथा खुमैनी से अपना फतवा वापस लेने का आग्रह किया। जार्ज बुश ने अपने एक बयान में ईरान को चुनौती देते हुए कहा, "अमरीकी नागरिकों की मौत की जिम्मेदारी खुमैनी की होगी।"

सेटेनिक वर्सेज की होली

ALMAN
RUSHDIE

कुछ भी हो, विश्व स्तर पर किये जा रहे विरोध और प्रदर्शनों का इतना तो असर है ही कि विश्व के बड़े-बड़े पुस्तक विक्रेताओं ने अपने काउंटरों से 'सेटेनिक वर्सेज' हटा दी है। हालांकि एक सूचना में बताया गया है कि विश्व स्तर पर हो रहे विरोध के कारण रुश्दी के उपन्यास की मांग बढ़ गयी है, किंतु वितरक उपन्यास बेचते हुए घबरा रहे हैं, क्योंकि ईरानी कट्टरपंथियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी है।

राजनीतिक पक्ष: दूसरी ओर राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मत है कि दुनिया भर में रुश्दी की पुस्तक को लेकर जो हंगामा खड़ा किया गया है, उसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ मौजूद हैं। इस तरह का मत रखने वाले लोगों का कहना है कि खाड़ी युद्ध विराम के बाद से खबरों से लगभग गायब हो गये अयातुल्ला खुमैनी ने रुश्दी की किताब को ईरानी क्रांति के पुनर्जागरण का हथियार बनाया है। खाड़ी युद्ध विराम को लेकर विश्व में यह धारणा बनी थी कि ईरान में अतिउदारवादी लोगों को सत्ता में महत्व दिया जाने लगा है तथा कट्टरपंथियों का युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। युद्ध विराम के फैसले से अंदर-ही-अंदर कुढ़ रहे अयातुल्ला खुमैनी और उनका कट्टरपंथी दल मौके की तलाश में था, जिसका फायदा उठाकर धर्म के नाम पर नया विस्फोट किया जा सकता और ईरान में शिथिल हो रही कट्टर धार्मिक विचारधारा को जिंदा किया जा सकता। रुश्दी की किताब के आपत्तिजनक अंशों ने खुमैनी को उनका मनपसंद मौका दे ही दिया और वे पूरी कट्टरता के साथ उबल पड़े।

रुश्दी द्वारा क्षमायाचना: इस तरह का विचार व्यक्त करने वाले लोग तर्क के रूप में रुश्दी प्रकरण के क्षमा मांगने वाले दिन के दौरान ईरान से जारी होने वाले बयानों का सहारा लेते हैं। असल में हुआ यह था कि रुश्दी की हत्या के ऐलान के बाद इस तरह का ऐलान भी किया गया था कि यदि रुश्दी दुनिया के मुसलमानों से और इमाम खुमैनी से क्षमा मांग लेंगे, तो उनकी जान बच जायेगी। मौके की

हिंसक प्रतिवाद

देखते-देखते इस पुस्तक को लेकर ऐसा बावेला खड़ा हुआ कि श्रीनगर और बंबई में दंगे भड़क उठे, जिनमें पंद्रह-सोलह बेगुनाह लोगों की जानें गयीं और सैकड़ों जख्मी हुए।

नजाकत को देखकर रुश्दी ने क्षमा मांगना उचित समझा और अपना बयान जारी किया, "यदि मेरे उपन्यास 'द सेटेनिक वर्सेज' से किसी की भावना को ठेस पहुची है, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।" रुश्दी के इस बयान पर ईरान से मिलने वाली पहली खबर में कहा गया कि ईरान ने उनको क्षमा कर दिया, किंतु उसके तुरंत बाद ही एक विपरीत बयान जारी हुआ, "चूंकि रुश्दी ने आम मुसलमानों से साफ तरह से माफी नहीं मांगी और अपनी पुस्तक वापस लेने का वचन नहीं दिया, इसलिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता।" एक ही मसले पर एक ही दिन में दो अलग-अलग तरह के बयानों से ईरानी सत्ताधीशों के अंतर्विरोध का संकेत मिला। इसी तरह इस्लामाबाद के अमरीकी सांस्कृतिक केंद्र के सामने रुश्दी के उपन्यास के खिलाफ प्रदर्शन को भी इस खेमे के लोग राजनीति से परिपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि जिया समर्थक कट्टरपंथी बेनजीर भुट्टो की सरकार को कमजोर करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अपने मत को तर्कसंगत करने के लिए वे प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के इस बयान, "क्या सचमुच आंदोलन रुश्दी की उस किताब के लिए छेड़ा गया है, जिसे न तो किसी ने पढ़ा है, न ही वह पाकिस्तान में उपलब्ध है और न ही उसका पाकिस्तान में अनुवाद हो रहा है? या इस आंदोलन का उद्देश्य पाकिस्तान में लौटे लोकतंत्र को कमजोर करना है?" का सहारा लेते हैं।

खिलाफत लाजिम : यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया भर में रुश्दी के चौथे उपन्यास को लेकर जो बावेला खड़ा हुआ है, वह अकारण है। यद्यपि रुश्दी का कहना है कि उनका उपन्यास इतिहास या धर्मशास्त्र पर आधृत नहीं है, बल्कि उनकी कल्पना की उपज है, लेकिन वे यह मानते हैं कि इसमें उन्होंने अपने नजरिये से धर्म को देखा है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाये, तो पात्रों के नाम और घटनाएं इतिहास का आभास देती हैं और वह इतिहास धार्मिक आस्था का अंग है।

रुश्दी ने अपने उपन्यास 'द सेटेनिक वर्सेज' में इस्लाम को अपनी कल्पना की उड़ान और कलम के जोर का निशाना बनाया है। उपन्यास में सलमान नाम का एक चरित्र है, जो ईश्वर के फरमान को महूंद से सुनकर लिखता है। उल्लेखनीय है कि महूंद रुश्दी का काल्पनिक पैगंबर है, लेकिन रुश्दी के इस पात्र का साम्य मुसलमानों के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब से बैठता है। रुश्दी अपने उपन्यास में सलमान की शरारत का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सलमान महूंद द्वारा दोहराये गये खुदा के फरमान को बदल कर लिख देता है। जब रुश्दी के पैगंबर को यह अहसास होता है कि सलमान ने खुदा के फरमान को तोड़-मरोड़कर लिखा, तो रुश्दी का पैगंबर आगबबूला हो उठता है और कहता है, "तुमने जो गुनाह किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता।" रुश्दी लिखते हैं कि सलमान के गुनाह की वाजिब सजा तो मौत होती थी, किंतु महूंद इतने रहमदिल हैं कि वे सलमान की गलती माफ कर देते हैं।

निस्संदेह रुश्दी ने इस्लाम को जिस तरह से समझने और समझाने की कोशिश की है, वह आपत्तिजनक तो है ही। उनके हिसाब से तो खुदा का कोई फरमान सही नहीं लिखा गया, क्योंकि सलमान ने उसे बदल दिया। यह लिखकर रुश्दी ने मुसलमानों की मौजूदा धार्मिक पुस्तक कुरान की सत्यता पर सवालिया निशान लगाया है, जो धर्मप्राण मुसलमान के लिए असह्य है।

यही नहीं, अपने उपन्यास में कई जगह रुश्दी ने कुरान की आयतों को तोड़-मरोड़ कर समझने की कोशिश की है। एक जगह तो रुश्दी ने अपने पैगंबर महूंद को भी शैतान के बहकावे में आ जाने वाला दर्शाया है। अपने उपन्यास में रुश्दी लिखते हैं कि एक बार जिबरील (खुदा के फरमान को पैगंबर तक पहुंचाने वाले फरिश्ते जिनका वास्तविक नाम जिबराइल है) ने महूंद को बहका कर इस बात पर राजी कर लिया कि महूंद अपने धर्म के विरोधियों को शांत करने के लिए विरोधियों की तीन देवियों को स्वीकार कर लें और अपने एक खुदा के साथ उनकी (तीन देवियों) परस्तिश की भी छूट दे दें। जिबरील के बहकावे में आकर महूंद ने बात मान ली। किंतु बाद में जब जिबरील ने यह बताया कि उन्हें यह रास्ता शैतान ने दिखाया था, तो महूंद को अपनी गलती का अहसास हुआ। नतीजतन महूंद ने अपने उस हुक्म को रद्द कर दिया और उस हुक्म को अपने फरमानों से निकाल देने का भी आदेश दिया।

एक मामूली-सी समझ रखने वाला आदमी भी रुश्दी की उपर्युक्त शैली से इतना तो समझ ही सकता है कि रुश्दी का उद्देश्य सिवाय खुदा, उसके पैगंबर और जिबराइल पर उंगली उठाने के और कुछ नहीं। रुश्दी किसी तरह यह समझाने का प्रयास करते हैं कि पैगंबर भी शैतान के बहकावे में आ जाते थे, इसलिए जो फरमान आज के मुसलमानों के पास हैं, उनमें से कौन सा खुदा का है और कौन सा शैतान का यह कहा नहीं जा सकता। यही नहीं, रुश्दी ने अपने उपन्यास में मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का को 'जाहिलिया' का नाम दिया है। महूंद के शैतान के बहकावे में आने की बात लिखकर ही उन्होंने कुरान को अल्लाह के कलाम की जगह शैतान का कलाम बताने की कोशिश की है तथा उसी अध्याय से अपने उपन्यास का नाम 'सेटेनिक वर्सेज' रखा है।

इस्लाम और पैगंबर का मजाक उड़ाने का सिलसिला यहीं पर रुकता नहीं है। उपन्यास में आगे चलकर रुश्दी ने एक वेश्यालय का दृश्य तैयार किया है। उपन्यास का यही अंश सबसे सनसनीखेज और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। वेश्यालय में उपस्थित वेश्याओं का नामकरण करते समय रुश्दी को पैगंबर साहब की बीवियों के सिवा और कोई नाम नहीं मिला। दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने पैगंबर की बीवियों को अपनी मां का रुतबा देता है। रुश्दी की कलम को इतना लिखने के बाद भी चैन नहीं आया।

यद्यपि साहित्य की दृष्टि से भी यह उपन्यास कोई उच्चकोटि का नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मुद्दा बना कर रुश्दी की हत्या करने के फरमान का साहित्य जगत में विरोध हुआ है। यही नहीं, रुश्दी के समर्थन में साहित्यकारों के संगठन अमरीकी पेन सेंटर के २२०० सदस्यों ने रुश्दी की सुरक्षा की मांग की है। इसके अतिरिक्त रुश्दी की तुलना सुकरात, गैलिलियो तथा सैवोनारोला जैसे ऐतिहासिक पुरुषों से भी की गयी है। एक पश्चिमी साहित्यकार ने रुश्दी की वर्तमान स्थिति की मिसाल देते हुए लिखा है, "इतिहास का यह कोई पहला हादसा नहीं है। धर्म और तर्क की लड़ाई तो युगों से चली आ रही है। इस संबंध में गैलिलियो का नाम उल्लेखनीय है। उस जमाने में चर्च की धारणा थी कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलिलियो ने अपनी खोजों से पता चलाया कि चर्च की धारणा गलत थी। सचाई तो यह थी कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। इस बात को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उसकी

परिणति यह हुई थी कि गैलिलियो को जान से मारने का आदेश दिया गया था। जान बचाने के लिए गैलिलियो ने क्षमा मांगी थी, किंतु पादरियों के समक्ष जब गैलिलियो क्षमा मांग रहे थे, तो आहिस्ता से कह रहे थे, "क्षमा तो मांग रहा हूं, किंतु सच यही है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है।"

इस्रायल का रुख: रुश्दी के समर्थन में पश्चिमी साहित्यकार सुकरात और गैलिलियो के उदाहरण तो पेश कर रहे हैं, किंतु उन मध्यकालीन नाटकों का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनमें इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिशें की जाती थीं और मुस्लिम समुदाय बौखला उठता था। उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन अंग्रेजी नाटकों में जान-बूझकर इस्लाम को बदनाम करने तथा उसका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब से मिलता-जुलता बिगड़े नाम का चरित्र महूंद पेश किया जाता था, जिसके माध्यम से इस्लाम, कुरान और पैगंबर का मजाक उड़ाया जाता था। इन नाटकों को प्रस्तुत करने में अकसर यहूदी आगे-आगे होते थे। हाल के बवंडर के दौरान इस्रायल ने रुश्दी को पनाह देने की घोषणा करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि रुश्दी की पुस्तक कुछ और नहीं उन्हीं मध्ययुगीन अंग्रेजी नाटकों की एक कड़ी है, जिनका इस्तेमाल मध्यकाल में इस्लाम के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए किया जाता था। ऐसे में यदि कोई यह कहे कि रुश्दी ने कश्मीरी मुस्लिम घराने में जन्म (वैसे रुश्दी के नाना अलीगढ़ के नामी बट परिवार के थे और उनके मामा महमूद बट इलाहाबाद में प्रशासक रह चुके हैं) जरूर लिया, किंतु चूंकि बचपन से ही वे पश्चिमी नजरिये के हामी रहे, इसलिए उन्होंने अपने धर्म को भी पश्चिमी नजरिये से समझने की कोशिश की है, तो अतिशयोक्ति न होगी। जाहिर है, 'द सेटेनिक वर्सेज' के काल्पनिक पैगंबर महूंद और मध्ययुगीन अंग्रेजी नाटकों के शैतानी पैगंबर महूंद में कोई खास फर्क दिखायी नहीं देता। इसलिए रुश्दी की कल्पना को इक्कीसवी शताब्दी की प्रगतिशीलता से जोड़ना उचित न होगा, क्योंकि इसकी जड़ें, तो मध्ययुगीन धर्मांधता के अंधकार में पैबस्त हैं। दूसरे शब्दों में यदि यह कहा जाये कि रुश्दी ने ईसाई-मुस्लिम धार्मिक विरोध को नया आयाम दिया है, तो अनुचित न होगा।

बहरहाल सलमान रुश्दी ने जो कुछ लिखा है, उसे लेकर जो बावेला मचा है, उसकी परिणति क्या होगी यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जायेगा कि सेटेनिक वर्सेज की रचना से रुश्दी ने अपनी प्रगतिशीलता का परिचय न देकर मानसिक संकीर्णता का परिचय दिया है। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि ईरान ने यह कहकर ब्रिटेन से राजनयिक संबंध तोड़ लिया है कि ब्रिटेन रुश्दी की शरारत में मदद कर रहा है। यही नहीं, जहां ब्रिटिश सरकार को प्रतिदिन ४,००० पाउंड रुश्दी की सुरक्षा पर खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं रुश्दी जीवित होते हुए भी दूर कहीं अज्ञात जगह पर अपनी अमरीकी लेखिका पत्नी मरियाने विगिस के साथ प्रतिदिन सौ-सौ बार मौत के मुंह से निकल रहे हैं। यहीं नहीं रुश्दी प्रकरण को लेकर पूरब और पश्चिम जिस तरह से दो खेमों में बंटे है, वह भी ठीक नहीं है। इस धर्मयुद्ध का अंजाम क्या होगा, यह कहा नहीं जा सकता। कितनी अजीब बात है कि उत्तरी लंदन स्थित अपने चार मंजिला मकान के जिस अध्ययनकक्ष में बैठकर प्रतिदिन ८०० शब्द की रफ्तार से रुश्दी ने 'द सेटेनिक वर्सेज' की रचना की थी, आज वह कक्ष स्काटलैंड यार्ड के आतंकवाद विरोधी दस्तों की सुरक्षा में सुनसान पड़ा है।

—तारिक खान

नया सिलसिला

अपने स्वतंत्र विचारों के कारण अयातुल्ला खुमैनी से मौत का फतवा सुनने वाले सलमान रुश्दी पहले आदमी नहीं हैं। पहला शिकार थे अहमद कसरावी नामक ईरानी सैयद, जो मुल्ला बनने के लिए मदरसे में दाखिल हुए, लेकिन धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम पर बहस-मुबाहिसे की जुर्रत की थी। कसरावी को अपने विचारों पर इतना पक्का भरोसा था कि उन्होंने मुल्लाओं को खुली बहस की चुनौती दी। जिन कई मौलवियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, वे बहस में टिक नहीं पाये। खुमैनी भी इनमें से एक थे। लेकिन खुमैनी अन्य मुल्लाओं की तरह अपनी हार स्वीकार करके चुप बैठ जानेवाले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिसमें मुल्ला (इस्लामी जज) किसी के भी खून को 'फालतू' बता सकता था, अर्थात उसे मृत्युदंड दे सकता था। कसरावी के खून को भी 'फालतू' घोषित किया गया। खुमैनी के फैसले पर अमल हुआ और कसरावी की हत्या छुरा भोंककर कर दी गयी। खुमैनी के दोस्त अयातुल्ला शेख सादेक खलखली ने लिखा, "यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन है। हम सभी जानते हैं कि अपराधी को अल्लाह के हाथों सजा मिली है और इस्लाम फिर से जिंदा रह सकेगा।"

दरअसल खलखली ने खुमैनी के जल्लाद की प्रमुख भूमिका निभायी है। ११ फरवरी १९७९ को ईरान में शाह की सत्ता उखाड़ फेंकने के चार दिन बाद ही खलखली ने तेहरान के एक स्कूल में एक न्यायिक पंचाट की गुप्त बैठक आयोजित की, जिसमें खुमैनी ने शाह के चार बड़े कमांडरों को मौत की सजा सुनायी थी। इन चारों को अगले दिन सुबह ही मौत के घाट उतार दिया गया। १४ मार्च तक शाह के शासन से जुड़े ७० लोगों को खलखली के आदेश से मौत के घाट उतार दिया गया था। अधिकांश लोगों को फांसी उसी इमारत की छत से लटका कर दी गयी, जहां खुमैनी अपनी अदालत लगाते थे। ७ अप्रैल को खलखली ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अमीर अब्बास होवैदा को फांसी की सजा सुनायी और कुछ घंटों के अंदर ही उन्हें फांसी दे दी गयी।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार १२ अगस्त, १९७९ तक ४३८ लोगों को फांसी दी गयी थी और १३ अगस्त से १४ सितंबर १९७९ के बीच १२० और लोगों को मौत की सजा सुनायी गयी। नवंबर तक तेहरान में ५५० और प्रांतों में १००० से अधिक लोगों को फांसी दे दी गयी थी। मरनेवालों में शाह के मंत्री, संसद सदस्य, बड़े अधिकारी, सेना और पुलिस के अधिकारी, व्यापारी और कुर्द विद्रोही शामिल थे। एक गैर कुर्दिश डाक्टर रशवंद सरदारी को किसी घायल कुर्द विद्रोही का इलाज करने के लिए भी फांसी दी गयी थी। ईरान के बाहर और अंदर से भी मामलों की खुली सुनवाई की सारी अपीलों को खुमैनी ने यह कह कर ठुकरा दिया कि 'अपराधियों की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें मार डालना चाहिए।

२०, मई १९८० को खलखली को नशीले पदार्थों और सेक्स संबंधी अपराधों वाले मामलों का जज बनाया गया। इससे मौतों का एक और दौर शुरू हुआ। अधिकांश लोगों को तेहरान की सड़कों पर सबके सामने गोली से उड़ाया गया। एक मामले में यौन अपराध के आरोप वाले दो मर्दों और दो औरतों को सफेद पोशाकें पहनाकर सीने तक मिट्टी में गाड़ दिया गया और फिर पत्थरों से मार कर उन्हें मौत के हवाले कर दिया गया। एक अन्य मामले में खलखली ने यौन अपराधों और नशीले पदार्थों का धंधा करने के आरोप वाले आठ लोगों को सार्वजनिक तौर पर फांसी दिये जाने का आदेश दिया। तेहरान की एक सड़क पर फांसी का तख्ता बना और सजा पाये लोगों को पेप्सीकोला और कोका-कोला के खाली डिब्बों पर खड़ा कराया गया। उनके गले में फांसी के फंदे लगाये गये। पर जैसे ही उनके पैरों के नीचे से डिब्बे हटाये गये, फांसी का तख्ता ही गिर गया। बाद में इन आठों को गोलियों से उड़ा दिया गया। जनवरी तक ९०६ लोगों को मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति बानी सदर ने खलखली से इस्तीफा ले लिया। लेकिन उनके खिलाफ उनकी अनियंत्रित रक्त-पिपासा को कारण नहीं बताया गया, बल्कि छापों में पकड़े गये १.४ करोड़ की रकम का हिसाब नहीं रख पाने की अक्षमता को कारण बताया गया। इसके बाद परिस्थितियों ने ऐसा पलटा खाया कि बानी सदर को दर-बदर हो कर पेरिस में पनाह लेनी पड़ी। अब फिर से मौत के फरमान जारी होने लगे हैं और इसकी वजह से खलखली के नये सिरे से हावी होने के संकेत हैं।

—जॉय राफेल, रियाद से

भारत का वेस्टइंडीज दौरा

ऊंट किस करवट बैठेगा ?

१६ सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम अपने प्रबंधक एस वेंकटराघवन तथा प्रकृति चिकित्सक डाक्टर पी कानन के साथ पांच एक दिवसीय तथा चार टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज टीम से मुकाबला करने के लिए कमर कसकर वेस्टइंडीज के दौरे पर रवाना हो चुकी है। भारतीय टीम के हौसले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस बार मेजबानों को पछाड़ने की उसने कसम खा रखी है, किंतु इस सचाई को नजरअंदाज करना उचित न होगा कि पिछले एक वर्ष में वेस्टइंडीज की टीम ने अपने आपको काफी संभाला है तभी उसका प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

कैरेबियन खिलाड़ी अपने भूतपूर्व कप्तान क्लाइव लायड के टेस्ट क्रिकेट संसार से सन्यास लेने के पश्चात भटक जरूर गये थे, किंतु अब उन्होंने अपने आपको उस भंवर से बाहर निकाल लिया है। अपने विश्व विजय अभियान में वे एक बार फिर एकजुट हो गये हैं। इसलिए जहां भारतीय टीम के वेस्टइंडीज भ्रमण के रोचक रहने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर मेजबान टीम की शक्ति और प्रदर्शन के आधार पर भ्रमणकारी दल के लिए यह दौरा चुनौतीपूर्ण भी है।

चयनकर्ताओं की सूझबूझ : चुनौतियों से जूझने के लिए भारतीय चयनकर्ताओं (अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर, भगवत चंद्रशेखर, रमेश सक्सेना, नरेंद्र तम्हाणे और चेतन चौहान) ने जो भी उदीयमान प्रतिभाएं उपलब्ध थीं उन्हें मद्देनजर रखते हुए एक संतुलित टीम का चयन किया है। हां, मोहिंदर अमरनाथ की समस्या को लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमी जनमानस अभी भी रुष्ट है तथा उसके टीम से निष्कासन का पूरा दोषारोपण चयनकर्ताओं के माथे ही मढ़ा जा रहा है। इसी प्रकार खब्बू फिरकी गेंदबाज मनिंदर सिंह के निष्कासन के औचित्य को भी चुनौती दी जा रही है। किंतु उसके बाद भी यह कहना अनुचित न होगा कि टीम का चयन संतुलित है। देखना तो अब यह है कि चयनित खिलाड़ी कैरेबियन में चुनौतीपूर्ण क्रिकेटीय परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं?

भारतीय भ्रमणकारी दल में चयनित सदस्यों के खेल के दमखम का यदि अवलोकन किया जाये, तो कहा जा सकता है कि जिस टीम में विश्व का एक श्रेष्ठ बल्लेबाज (कंप्यूटर के अनुसार तो सर्वश्रेष्ठ) दिलीप वेंगसरकर हो, जिसमें कपिल देव और रवि शास्त्री जैसे विश्व स्तरीय हरफनमौला खिलाड़ी हों, नरेंद्र हिरवानी जैसा नामी फिरकी गेंदबाज हो तथा जिस टीम में कृष्णमाचारी श्रीकांत जैसी मंजी हुई रन मशीन तथा मोहम्मद अजहरुद्दीन और संजय मंजरेकर जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हो वह संतुलित टीम तो है ही, साथ ही उभरते हुए खिलाड़ियों से भी परिपूर्ण है। मंजरेकर, अजय शर्मा, संजीव शर्मा, राबिन सिंह, सबा करीम और वेंकटरमणा का चयन इस तथ्य का परिचायक है कि चयनकर्ताओं ने चयन में भविष्य का ध्यान रखकर दूरदर्शिता का परिचय दिया है।

भारतीय क्रिकेट के भविष्य को देखते हुए तमिलनाडु के बायें हाथ के बल्लेबाज रमन का टीम में सम्मिलित न किया जाना या तो मजबूरी थी या अदूरदर्शिता। रमन की खब्बू बल्लेबाजी तथा १९८७-८८ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध प्रभावशाली प्रदर्शन ने भ्रमणकारियों पर जहां अपने कौशल की छाप छोडी थी, वहीं भारतीय बल्लेबाजी की साख को आंच भी नहीं आने दी थी।

क्रिकेट समीक्षकों और क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि दिल्ली के दो खिलाड़ी, कलात्मक बल्लेबाज केपी भास्कर और मध्यम तेज गेंदबाज (सही माने में तो हरफनमौला) मनोज प्रभाकर के साथ भी अन्याय हुआ है। क्योंकि घरेलू प्रतियोगिताओं में इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है।

सचाई यह है कि अब तक भास्कर का खेल दर्शनीय व मनमोहक रहा है। उसके क्रीड़ा कौशल पर गुण्डप्पा विश्वनाथ की दर्शनीय कलात्मक बल्लेबाजी की छाप साफ दिखायी देती है। लगता है टीम में मंजरेकर को शामिल किये जाने के कारण भास्कर बाजी हार गये और प्रभाकर को चेतन शर्मा और राबिन सिंह के कारण मैदान के बाहर समय व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया गया।

राबिन से जुड़ी उम्मीद : जहां तक राबिन सिंह (जो मूल रूप से त्रिनिदाद निवासी हैं और जिन्हें हाल में ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है) के चयन की बात है, तो उसका एक मात्र कारण यह है कि राबिन ने बचपन में क्रिकेट कैरबियन में खेला है, इसलिए वे कैरेबियन क्रिकेट से जुड़ी परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हैं। वे वेस्टइंडीज टीम के दांव-पेंच भलीभांति समझते हैं तथा उनके कौशल से भी अनभिज्ञ नहीं हैं। इसलिए हो सकता है राबिन की उपस्थिति से भारतीय टीम को फायदा पहुंचे।

इस बार वेस्टइंडीज जानेवाली भारतीय टीम में १९७१ से निरंतर टीम को चट्टाननुमा आधार प्रदान करने वाले सुनील गावस्कर नहीं हैं। शायद इसीलिए भारतीय बल्लेबाजी का ऊपरी क्रम डगमग-सा लग रहा है। जाहिर है, टीम को एक

आक्रमण की धार : संजय मंजरेकर

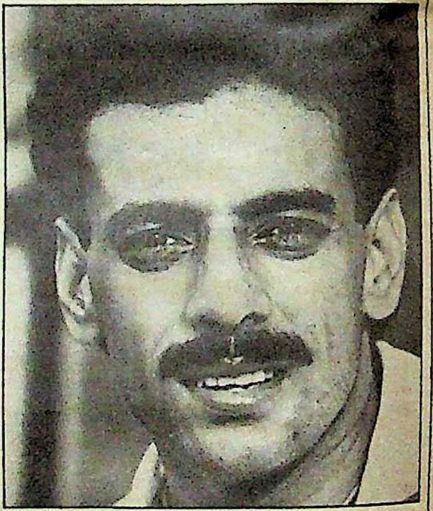

विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य : अजय शर्मा

कपिल के साथी : संजीव शर्मा

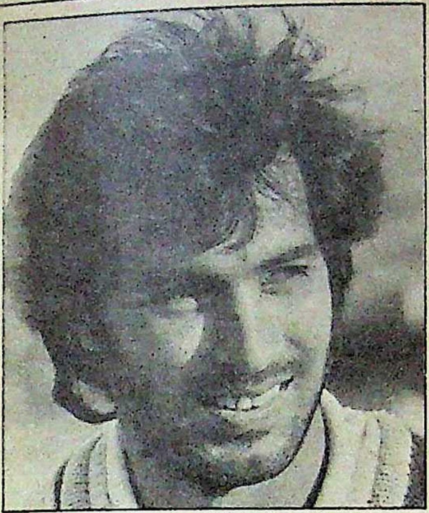

कौशल का कितना लाभ मिलेगा ? : राबिन सिंह

सही समय पर मौका : सबा करीम

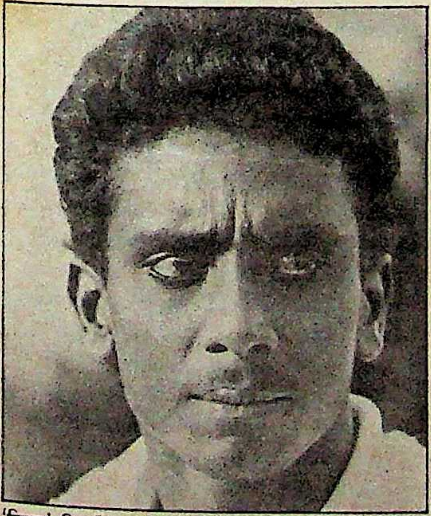

'स्पिन' निर्णायक दौर में : वेंकटरमणा

विश्वसनीय शुरुआत की आवश्यकता होती है। हालांकि इस भूमिका के लिए श्रीकांत और अरुणलाल की जोड़ी मौजूद है, किंतु यह जोड़ी कितनी सफल रहेगी यह कहा नहीं जा सकता। क्योंकि तेज-तर्रार तूफानी गेंदबाजों मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटर्सन कर्टली एंबरोस और कोर्टनी वाल्श के रणभेदी बाणों का सामना करना आसान बात नहीं है। इसलिए इस बात की संभावना है कि गावस्कर की अनुपस्थिति भारतीय बल्लेबाजों पर कैरेबियन में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव डालेगी जिससे टीम का मनोबल टूट सकता है। भ्रमणकारी दल को वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, कपिल देव और संजय मंजरेकर पर ही आश्रित रहना पड़ेगा।

यही नहीं किरण मोरे, चेतन शर्मा, अजय व संजीव शर्मा भी अच्छी मात्रा में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। रनों पर जोर देना इसलिए जरूरी है, क्योंकि बिना बड़ी मात्रा में रन बनाये भारतीय टीम का ठहरना मुश्किल है। समीक्षकों का कहना है कि भारतीय टीम के लिए प्रथम पारी में ३५० रन का लक्ष्य रखना ही उसे पराजय से बचा सकता है तथा गेंदबाजों को आक्रामक रवैया अपनाने का अवसर दे सकता है। यही नहीं, पिछले अनुभवों के अनुसार ३५० से अधिक रनों का लक्ष्य प्रायः वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से घातक सिद्ध होता है।

यहां पर कैरेबियन के दो मैदानों और वहां की खेल पट्टियों का विवेचन करना भी आवश्यक है। जमैका के सबाइना पार्क और बारबेडोस के कैंसिगटन ओवल मैदान के 'विकेट' जानदार व उछालभरे हैं। इन दोनों टेस्ट मैचों को यदि भारत बचा लेता है, तो कहा जा सकता है कि टीम अपनी लाज बचाने में सफल रही है और टक्कर ले सकने की क्षमता रखती है।

अच्छे स्कोर की जरूरत: दूसरी ओर त्रिनिदाद का क्वींस पार्क ओवल मैदान स्पिन गेंदबाजों के लिए वरदान है, क्योंकि वहां का वातावरण फिरकी गेंदबाजों को काफी भाता है। भारतीय 'स्पिनर' वहां वेस्टइंडीज टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकते हैं और पासा पलट सकता है। क्रिकेट इतिहास साक्षी है कि क्रमशः १९७१ और १९७६ में भारतीय टीम ने अपनी विजय का शंखनाद त्रिनिदाद में किया था। यही नहीं, गयाना के बोर्डा ओवल की खेल पट्टी भी हलका-सा 'स्पिन' लेती है और हिरवानी, शास्त्री और अरशद अयूब अपने करिश्मे दिखाकर मेजबान टीम के समक्ष भारतीय टीम का हौआ खड़ा कर सकते हैं। यहां पर इस बात पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है कि उपर्युक्त विश्लेषण का फायदा भारतीय टीम को तभी मिल सकेगा, जब उसका स्कोर अच्छा होगा।

जहां तक अनुभवी खिलाड़ी गोपाल शर्मा को नजरअंदाज किये जाने की बात है, तो कहा जा सकता है कि संभवतः चयनकर्ताओं ने भविष्य पर नजर रखकर तमिलनाडु के आफ 'स्पिनर' एम वेंकटरमणा को टीम में शामिल किया है। संभव है यह दौरा वेंकटरमणा के भावी क्रिकेट जीवन के लिए निर्णायक सिद्ध हो।

वैसे भी रमणा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें मैनेजर वेंकटराघवन के अनुभव का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। उल्लेखनीय है कि वेंकटराघवन १९७१, १९७६ और १९८३ में खिलाड़ी के रूप में वेस्टइंडीज जा चुके हैं और वहां की क्रिकेट परिस्थितियों से पूर्ण रूप से परिचित हैं।

जहां तक भारत-वेस्टइंडीज श्रृंखला के निर्णायक का प्रश्न है, तो यह कहना गलत न होगा कि इस श्रृंखला को अपने हक में मोड़ने में हिरवानी मददगार हो सकते हैं। उनकी सफलता अथवा विफलता से ही कैरेबियन में भारतीय टीम का भाग्य जुड़ा हुआ है। यदि यह कहा जाये कि हिरवानी ही भारत का तुरुप का पत्ता साबित होंगे, तो अनुचित न होगा। दूसरी ओर प्रारंभिक झटकों को सहन करने के लिए भारत को कपिल पर आश्रित रहना होगा। विशेषतया एक दिवसीय स्पर्धाओं में तो कपिल की भूमिका निर्णायक सिद्ध हो सकती है। आशा है संजीव शर्मा और चेतन शर्मा भी अपने चयन को सार्थक सिद्ध करने में सफल होंगे।

भारत-वेस्टइंडीज श्रृंखला का सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर है कि भारतीय बल्लेबाज वेस्टइंडीज के तूफानी गेंदबाजों का सामना कैसे करते हैं और मेजबान बल्लेबाज भारतीय स्पिन की गुत्थी सुलझाने में कितना सफल होते हैं ?

कांटे की टक्कर: उपर्युक्त विश्लेषण से जो नतीजे सामने आते हैं उनको आधार बनाकर यह कहा जा सकता है कि भारत-वेस्टइंडीज श्रृंखला का सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर है कि भारतीय बल्लेबाज वेस्टइंडीज के तूफानी गेंदबाजों का सामना कैसे करते हैं और मेजबान बल्लेबाज भारतीय स्पिन की गुत्थी सुलझाने में कितना सफल होते हैं? इसका यह मतलब नहीं कि क्षेत्र रक्षण (फील्डिंग) का कोई महत्व ही नहीं होगा। सचाई तो यह है कि सफलता की कुंजी क्षेत्र रक्षण ही है। इसके बाद बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इस दौरान वाकई परिस्थितियां कैसी बनती हैं। फिलहाल तो इतना ही कहना उचित होगा कि हाल का दौरा निस्संदेह रोचक रहेगा।

—रवि चतुर्वेदी

छाया: पंकज शर्मा

साक्षात्कार/कु० रिंकू गुप्ता

राष्ट्रीय जूनियर एवं सीनियर टेबल टेनिस विजेता

'टेनिस को भविष्य नहीं बनाऊंगी'

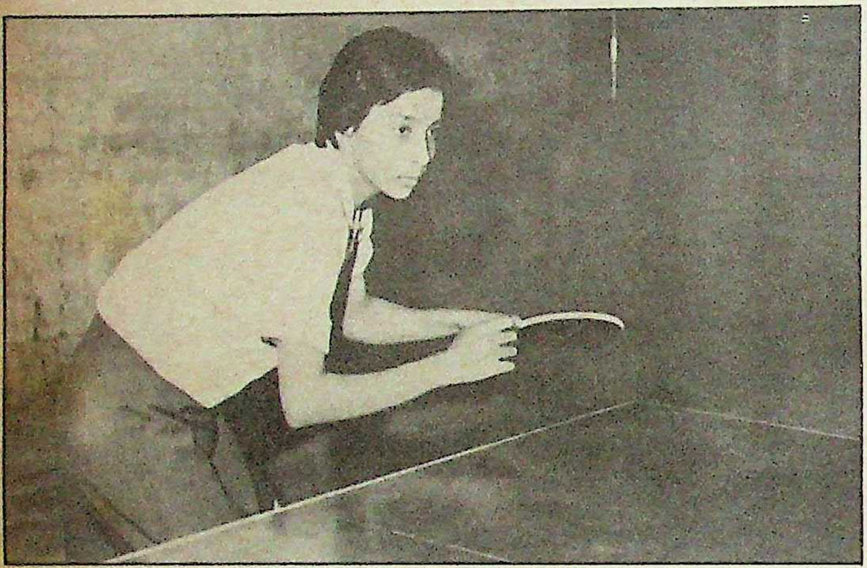

कीर्तिमान पर नजर: रिंकू गुप्ता

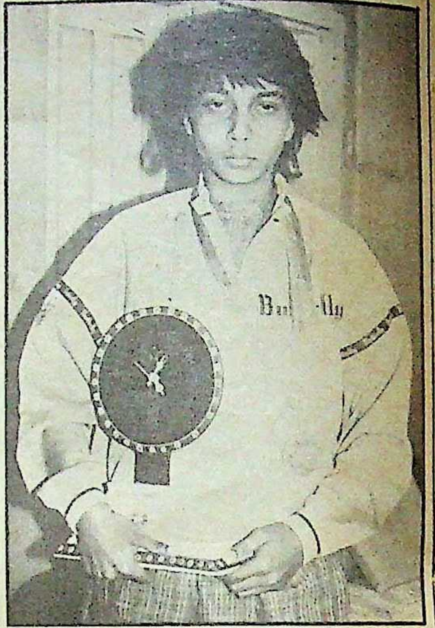

विजेता होने का गौरव: ट्राफी के साथ रिंकू गुप्ता

रोजाना चार घंटे अभ्यास और डेढ़ घंटे व्यायाम तथा ख्यातनामा खिलाड़ी स्निग्धा मेहता के हाथों छह माह गहन प्रशिक्षण—यह है, टेबल टेनिस की जूनियर एवं सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की १७ वर्षीया विजेता कुमारी रिंकू गुप्ता की सफलता का राज।

१३ फरवरी को हैदराबाद में खचाखचभरे लाल बहादुर इंडोर स्टेडियम में शाम करीब चार बजे रिंकू के वर्षा चुलानी के खिलाफ विजयी शाट लगाने की देर थी कि देश में टेबल टेनिस के लगभग अर्धशती के इतिहास में सर्वथा नये कीर्तिमान का सृजन हो गया। पिछले साल वर्षा चुलानी ने १८ साल की उम्र में राष्ट्रीय खिताब जीतकर कीर्तिमान रचा था, जिसे इस साल सत्रह वर्ष की रिंकू ने वर्षा को हराकर तोड़ दिया। रिंकू ने एक और इतिहास यह रचा कि सन १९८५ में सब-जूनियर प्रतियोगिता जीतने के बाद उसने सन १९८६, ८७ और ८८ में जूनियर खिताब जीता और इस साल भी यानी चौथी बार लगातार जूनियर खिताब जीतने के बाद सीनियर खिताब भी अपनी झोली में डाल लिये। जीत के बाद रिंकू ने कहा, "मेरी जीत में सर्वाधिक हाथ स्निग्धा मेहता (खासगीवाला) का है। स्निग्धा मेरी प्रैक्टिस पार्टनर, प्रशिक्षक तथा आदर्श खिलाड़ी हैं।"

पिता रमेश गुप्ता और मां श्रीमती शकुन गुप्ता की लाडली बिटिया, सौम्य एवं अंतर्मुखी रिंकू अल्पायु में ही जापान, मिस्र व इंडोनेशिया में देश का प्रतिनिधित्व कर आयी है। नियोति राय को छोड़कर उसने यहां-वहां देश की सभी प्रमुख महिला टेबल टेनिस खिलाड़ियों को पराजित किया है। भारत में आठ बार राष्ट्रीय विजेता होने का श्रेय इंदु पुरी के नाम है और पूर्व राष्ट्रीय विजेता जी जगन्नाथ की पेशीनगोई है कि रिंकू दूसरी इंदु पुरी साबित होगी। मगर रिंकू कहती है कि वह टेनिस को अपना भविष्य नहीं बनायेगी। प्रस्तुत हैं, विक्रम अवार्ड विजेता रिंकू से 'माया' की बातचीत के मुख्य अंश:

माया: *आपने खेलना कब से प्रारंभ किया?*

रिंकू: *नौ साल की उम्र से।*

माया: *आपका टेबल टेनिस की ओर झुकाव किसी व्यक्ति के कारण हुआ या किसी घटना से?*

रिंकू: *नहीं, कोई घटना नहीं थी। मेरा झुकाव माता-पिता के कारण हुआ। वे दोनों ही घर में टेबल टेनिस खेलते थे और उनके मित्र भी खेलने आते थे। उन्हें खेलते देखकर मैं समझने-सीखने की कोशिश करती थी। बचपन में उन लोगों के साथ दो-चार बाल खेलने को मिल जाती थी, तो मैं बहुत खुश होती थी।*

माया: *मां-बाप ने आपको कभी टेनिस खेलने से रोका नहीं?*

रिंकू: *नहीं। उन्होंने सदैव मुझे प्रोत्साहित किया। पिताजी चाहते थे कि मैं इसी खेल में आगे बढ़ूं।*

माया: *इस साल जूनियर जीतने के बाद क्या आपको सीनियर जीतने का भी विश्वास था?*

रिंकू: *जूनियर प्रतियोगिता तो मैं पहले भी जीत चुकी थी। सवाल उस खिताब को मेहनत के बल पर बरकरार रखने का था। शुरू में तो मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं सीनियर खिताब भी जीत जाऊंगी।*

माया: *आप प्रायः एक जैसी सर्विस का प्रयोग करती हैं, जबकि वर्षा चुलानी की सर्विस में विविधता है। इंदु पुरी ने भी इस बारे में टिप्पणी की है कि अगर रिंकू को अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलना है, तो सर्विस में विविधता लानी होगी।*

रिंकू: *जी हां। मुझे भी लगता है कि अगर मुझे इंटरनेशनल मैचों में कुछ करना है, तो सर्विस सुधारनी होगी, जो मैं सबसे पहले करूंगी।*

माया: *आप अपनी जीत का श्रेय किसे देंगी?*

रिंकू: *स्निग्धा खासगीवाला को।*

माया: *क्या आप टेनिस को अपना कैरियर बनायेंगी?*

रिंकू: *मैं टेनिस को अपना भविष्य नहीं बनाऊंगी। मैं अभी बारहवीं 'क्लास में' हूं और सोच रही हूं कि एमबीए की परीक्षा दूं, क्योंकि मैंने कामर्स लिया हुआ है। मैं ग्रेजुएशन के बाद अहमदाबाद जाकर एमबीए करना चाहती हूं। आगे क्या बनूंगी, अभी मैंने गंभीरता से सोचा नहीं है।*

—एसपी त्रिपाठी 'आशु'

हेगड़े बुरे फंसे : पटना में 'जद' की बैठक में बगावत

विपक्ष के हर धड़े में बखेड़े

देश की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा चाहे कुछ भी हो, पर जब भी उससे बिहार का मुद्दा जुड़ता है तब एक बवंडर उठ जाता है, बवाल मच जाता है। जनता दल में प्रांतीय अध्यक्षों के चयन के दौरान रघुनाथ झा के मुद्दे पर चंद्र शेखर और वीपी सिंह में छिड़ा द्वंद्व भी कमजोर बखेड़ा नहीं था। माकपा और भाजपा में भी बिहार के सवाल पर बवाल मचा है। यदि ये विपक्षी पार्टियां आपस में ही लड़ती रहीं, तो क्या कांग्रेस का विकल्प बन सकेंगी ?

बिहार इधर कुछ दिनों से देश की राजनीति में एकदम फांस की तरह गड़ा हुआ है। देश की सत्ताधारी पार्टी में पिछले दिनों उभरी बगावत की धुरी बिहार ही था, जब इंका के विद्रोही विधायकों ने पटना की सड़को पर उतरकर आलाकमान को बुरी तरह सांसत में डाल दिया था। जनतादल में भी बिहार के मसले ने ही देश की विपक्षी राजनीति के दो धुरंधर ठाकुरों विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर में मुठभेड़ करवा दी। पर बिहार को लेकर सिर्फ जनतादल में ही आपाधापी नहीं मची है, बल्कि प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों में कमोबेश अंदरूनी संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जहां प्रांतीय अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाशपति मिश्र का तनाव निरंतर गहराता जा रहा है, वहीं माकपा की बिहार शाखा में छिड़ा दंगल भी संगीन होता जा रहा है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में बिहार माकपा के एक दिग्गज नेता योगेश्वर गोप जब पार्टी से निकाल दिये गये, तो विवाद और तूल पकड़ गया।

चंद्रशेखर की चाल : बिहार को मुद्दा बनाकर चंद्रशेखर ने जनतादल में ऐसी चाल चल दी कि अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह और महासचिव अजीत सिंह के हलक सूख गये। अपने गृहराज्य उत्तर प्रदेश में अपने किसी ख़ासुलख़ास को जनतादल के अध्यक्ष पद पर काबिज कराने के लिए चंद्रशेखर कभी उत्सुक नहीं रहे। पर बिहार में अपने प्रत्याशी रघुनाथ झा को अध्यक्ष पद की बागडोर दिलवाने के

चंद्रशेखर का सहारा: मंच पर चंद्रशेखर के पीछे रघुनाथ झा

लिए चंद्रशेखर ने देवीलाल के संग गोट जमाकर जो कुछ भी किया, उससे ऊपरी तौर पर तो यही साबित हुआ कि चंद्रशेखर को राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए सहूलियत का समीकरण बनाने के बजाय एकमात्र बिहार की ही राजनीति में दिलचस्पी है। पर ऐसी बात नहीं थी। कहते हैं, चंद्रशेखर को विश्वनाथ प्रताप सिंह और अजीत सिंह से खुंदक का बदला लेना था और इसके लिए यह जरूरी था कि देश की संसद में सर्वाधिक सांसद भेजनेवाले दो प्रांतों उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश के इन दोनों नेताओं के हाथों में न रहे। इसी महीन रणनीति के तहत चंद्रशेखर ने वर्तमान विपक्षी राजनीति के महत्वाकांक्षी वयोवृद्ध नेता देवीलाल को जनता दल संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रांतीय अध्यक्षों के मनोनयन के सवाल पर खुला समर्थन दिया। दरअसल, चंद्रशेखर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि देवीलाल हरियाणा में जहां अपने बेटे ओमप्रकाश चौटाला को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के लिए भी एड़ीचोटी एक करेंगे। लिहाजा, चंद्रशेखर ने देवीलाल को धर्मसंकट से बचाने के लिए ओमप्रकाश चौटाला के नाम का पहले समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर समझते थे कि देवीलाल अगर अपने बेटे के नाम को ही स्वीकार करवाने में अपनी ऊर्जा खो बैठे, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नाम पर वे जोर से नहीं डटेंगे। फिर या तो विश्वनाथ प्रताप सिंह या अजीत सिंह उत्तर प्रदेश में बाजी मार ले जायेंगे। चंद्रशेखर की यह कूटनीति कारगर हुई और देवीलाल मुलायम सिंह यादव के लिए बिलकुल अडिग हो गये। चंद्रशेखर का तीर बिलकुल निशाने पर जा लगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मामले में जब देवीलाल, चंद्रशेखर की शह से कारगर हो गये, तब चंद्रशेखर ने बिहार का पासा फेंका और अपनी तरफ से बिहार में जनतादल के अध्यक्ष पद के लिए रघुनाथ झा का नाम पेश कर दिया। रघुनाथ झा को अपने उम्मीदवार के रूप में उछालकर चंद्रशेखर ने टकराव की ऐसी स्थिति खड़ी कर दी जिसके लिए वे स्वयं देर से उत्सुक थे। देवीलाल के लिए भी यह विवशता हो गयी थी कि वे बिहार के सवाल पर चंद्रशेखर को समर्थन दें।

चंद्रशेखर ने अपने कोटे में बस एक नाम रघुनाथ झा का रखा था और वह अगर विफल हो जाता, तो चंद्रशेखर के उखड़ने का रास्ता खुल जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह बिहार में भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने का मन बनाये बैठे थे। इधर चंद्रशेखर अपनी जिद पर अड़े हुए थे। २० फरवरी को दिल्ली में जनता संसदीय बोर्ड की बैठक में आखिरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह आपा खो बैठे और फिर चंद्रशेखर से उनकी बिहार के सवाल पर तेज झड़प हो गयी। गुस्से में विश्वनाथ प्रताप बोर्ड की बैठक से उठकर बाहर चले गये। स्थिति बेकाबू होती देख महासचिव अजीत सिंह और उनके पीछे-पीछे मुलायम सिंह यादव और शरद यादव विश्वनाथ प्रताप सिंह को मनाकर लाने गये और किसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह को फिर से बैठक में बिठा सके। अजीत सिंह को पहले ही खिन्न कर विश्वनाथ प्रताप सिंह को बौखलाने के अपने मिशन में चंद्रशेखर सौ फीसदी सफल हो चुके थे। पर विश्वनाथ प्रताप की नाराजगी के बावजूद वे बिहार के मसले पर अटल थे। आखिरकार विश्वनाथ प्रताप को ही हथियार डालना पड़ा। इस तरह दो बड़े हिंदीभाषी प्रांतों की राजनीति चंद्रशेखर ने विश्वनाथ प्रताप और अजीत सिंह से झटक ली। विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रत्याशी रामसुंदर दास को तो चंद्रशेखर ने इस सफायी से काटा कि बिहार में अजीत खेमा भी सकते में आ गया। बिहार विधानसभा में विधायकदल के नेतापद के लिए चंद्रशेखर ने देवीलाल समर्थक लालू यादव के नाम पर सहमति जता दी, तो अजीत गुट के १३ विधायक हतप्रभ रह गये, क्योंकि बिहार में भी उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। रामसुंदर दास विधानसभाई चुनाव में लालू यादव से पराजित हो चुके हैं और दोनों सारण जिले के ही नेता हैं। एक ही जिले के इन दो नेताओं को पार्टी का अध्यक्षपद और विधायकदल का नेतापद कैसे दिया जाये? जनता दल संसदीय बोर्ड में रामसुंदर दास की उम्मीदवारी को कमजोर करने में यह तर्क भी रंग लाया। वैसे जनतादल के अध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े भी रामसुंदर दास की तरफदारी इसलिए जोरशोर से कर रहे थे, क्योंकि चंद्रशेखर से अपनी रंजिश का हिसाब लेने के लिए वे विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दे रहे थे। रघुनाथ झा के विरोध में बस एक यही बात उठायी गयी कि उनका संबंध इंका के बागी नेता डा० जगन्नाथ मिश्र से है। पर इस बात को तत्काल कारगर ढंग से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि अब रघुनाथ झा के रिश्ते डा० जगन्नाथ मिश्र से पहले की भांति नहीं हैं। रामसुंदर दास के बारे में यह बात-साबित की गयी कि वे कहीं से 'डायनेमिक' नहीं हैं इसलिए आम चुनाव के रणक्षेत्र में वे किसी सूरत में नहीं जम पायेंगे। रघुनाथ झा के नाम पर सहमति जाहिर करनेवालों का तर्क था कि जिस तरह कांग्रेस के बारे में यह धारणा बन गयी है कि वहां राजपूतों के लिए जगह नहीं उसी तरह जनतादल के बारे में भी यह धारणा बन रही है कि जनतादल में ब्राह्मणों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसलिए बिहार जैसे राजनीतिक चेतना वाले प्रांत में रघुनाथ झा को अध्यक्ष बनाया जाता है, तो जनता दल ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप का प्रतिकार कर सकता है।

दुश्मनों से दोस्ती: २० फरवरी को रघुनाथ झा को बिहार जनतादल का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इस मनोनयन के विरोध में रामसुंदर दास, कपिलदेव सिंह, चंद्रदेव वर्मा, कमला सिंह और बैद्यनाथ मेहता आदि ने पटना में २२ फरवरी को बयान जारी कर कहा कि बिहार में जनतादल का एक कदम चलना संभव नहीं हो पायेगा और जनता दल संसदीय बोर्ड का फैसला वे लोग नहीं मानेंगे। इन विक्षुब्ध नेताओं ने चंद्रशेखर पर भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर जनतादल के साथ भितरघात कर रहे हैं। जनता दल के इन बागी नेताओं ने मुनादी कर दी कि अगर एक सप्ताह में इस मामले पर संसदीय बोर्ड ने पुनर्विचार नहीं किया, तो वे लोग १८ मार्च को विपक्षी कार्यकर्ताओं का पटना में अधिवेशन करेंगे। २२ फरवरी को, जब जनतादल के बागी नेता पटना में बिफर रहे थे, दिल्ली से रघुनाथ झा और लालू यादव एक साथ पटना पहुंचे। इन दोनों नेताओं की अगवानी में उनके समर्थक जिस उत्साह से भारी संख्या में तत्पर थे उसने साबित कर दिया कि चंद्रशेखर और देवीलाल की संयुक्त राजनीति ही जनतादल की अब असली राजनीति है। देवीलाल ने कहा भी कि जिस चंद्रशेखर को उन्होंने 'कांग्रेसी एजेंट' और क्या कुछ नहीं कहा था, उसी चंद्रशेखर ने बड़प्पन से उनका साथ दिया। पर दोनों नेता दिल ही दिल में इस तथ्य से वाकिफ हैं कि यह दो दुश्मनों के बीच सुविधा का समीकरण भर है। २२ फरवरी को रघुनाथ झा ने पटना आते ही कहा कि उनके दिल में उन नेताओं के प्रति भी सम्मान है, जो उनसे मतभेद रखते हैं और वे सामूहिक नेतृत्व के फार्मूले से जनतादल का संचालन करेंगे। २३ फरवरी को रामकृष्ण हेगड़े पटना पहुंचे, तो जनता दल के नाराज नेताओं को मौका मिल गया। पटना में हेगड़े की मौजूदगी में हुई जनतादल की बैठक में मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गयी और उस हंगामे के बीच हेगड़े हतप्रभ खड़े रहे। आखिरकार खिन्न होकर हेगड़े को कहना पड़ा, "आप लोग अगर इस तरह लड़ते रहेंगे, तो राजीव गांधी को सत्ता से हटाने का सपना मत देखिये।" हेगड़े के पटना से जाने के दो दिन बाद स्वयं चंद्रशेखर पटना पहुंचे। शुरू में लग रहा था कि

चंद्रशेखर को पटना में कड़ा विरोध नहीं झेलना पड़ेगा, पर चंद्रशेखर जब पटना पहुंचे, तो स्थिति पलट गयी और रामसुंदर दास, नवलकिशोर शाही सरीखे अन्य सभी नेताओं ने इस बात का खंडन किया कि वे लोग चंद्रशेखर को 'पार्टी-तोड़क' कह रहे थे। हाजीपुर में चंद्रशेखर की सभा में रघुनाथ झा के संग रामसुंदर दास भी मौजूद थे। चंद्रशेखर ने इस बात का भी पटना में खंडन किया कि रघुनाथ झा के मनोनयन के सवाल पर उनकी विश्वनाथ प्रताप सिंह से झड़प हुई थी। चंद्रशेखर ने कहा कि रघुनाथ झा का नाम बहुत सहजता से तय हो गया था। रघुनाथ झा 'माया' से कहते हैं, "अब समय नहीं है कि कोई दूसरी बात सोची जाये। जनतादल के लिए जन-लहर बिहार में तैयार करने के लिए एक-एक कार्यकर्ता को जुट जाना है।"

राम सुंदर दास

योगेश्वर गोप

राम दास राय

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा का मतभेद तब सुर्खियों में आ गया, जब गणेशशंकर विद्यार्थी ने योगेश्वर गोप को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी और कहा, "६ सितंबर, १९८८ को बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल में गोप ने भितरघात किया जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची।"

माकपा में उठापटक: फरवरी के दूसरे सप्ताह में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) बिहार शाखा का मतभेद तब सुर्खियों में आ गया जब पार्टी की राज्य समिति के सचिव गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपनी पार्टी के एक प्रमुख नेता योगेश्वर गोप को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी और कहा, "६ सितंबर, १९८८ को बिहार में कर्मचारियों की हड़ताल में गोप ने भितरघात किया जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया। गणेशशंकर विद्यार्थी का आरोप था कि गोप को एक बार पहले चेतावनी दी गयी, फिर भी वे 'बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ' में महज अपना वर्चस्व रखने के लिए जोड़तोड़ करते रहे। दूसरी तरफ योगेश्वर गोप ने अपने निष्कासन के बाद आरोप लगाया कि पार्टी सचिव (विद्यार्थी) उनके ठोस जनाधार से काफी दिनों से परेशान थे और यह खतरा महसूस करने लगे थे कि वे (गोप) उन्हें पार्टी सचिव पद से कभी भी अपदस्थ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को बरगला कर निष्कासन का फैसला करवा दिया। योगेश्वर गोप 'माया' से कहते हैं, "गणेशशंकर विद्यार्थी ने पार्टी में जब कभी किसी को शक्तिशाली होते देखा, तो षड्यंत्र कर उसे पार्टी से निकलवा दिया। उदाहरण के लिए धनबाद के पूर्व सांसद एके राय, तकी रहीम, अर्जुन प्रसाद, रासबिहारी सिंह सरीखे जनाधार वाले नेताओं को उन्होंने साजिश कर पार्टी से बाहर कर दिया। अब मेरे बाद उनकी नजर नंदकिशोर शुक्ल तथा बिहार में सीपीएम के एकमात्र विधायक अजित सरकार पर गड़ी हुई है।" दरअसल सीपीएम के बिहार में इकलौते विधायक अजित सरकार ने भी योगेश्वर गोप के पार्टी से निष्कासन का अंत तक विरोध किया था। अजित सरकार 'माया' से कहते हैं, "योगेश्वर गोप के निष्कासन पर कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है।" जाहिर है, वे निष्कासन का समर्थन करने में किसी सूरत में तैयार नहीं हैं। आखिर गोप के निष्कासन की जड़ में क्या बात है? गोप के समर्थक बताते हैं कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों की यूनियन में योगेश्वर गोप का वर्चस्व रहा है और गोप से मतभेद होने के कारण गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपनी पार्टी के एक नेता योगेंद्र सिंह को गोप की काट में खड़ा करना शुरू किया। १९८८ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का आह्वान जब योगेंद्र सिंह ने किया, तो योगेश्वर गुट की यूनियन योगेंद्र के आह्वान पर हड़ताल में नहीं उतरी। योगेश्वर गोप 'माया' से कहते हैं, "योगेंद्र सिंह को गणेशशंकर विद्यार्थी पूरी शह दिये हुए थे और इसका एकमात्र मकसद था मुझे नीचा दिखाना। इसके पीछे राजनीति यह थी कि कर्मचारी हड़ताल की सफलता की स्थिति में पार्टी के भीतर यह साबित किया जाता कि योगेश्वर गोप के विरोध के बावजूद हड़ताल सफल रही, इसलिए गोप का कर्मचारियों पर कोई असर नहीं। हड़ताल विफल होने की स्थिति में यह कहा जाता कि गोप ने विरोध कर हड़ताल विफल करवा दी। बिहार में कुल आठ लाख कर्मचारी हैं। इनमें से मात्र एक लाख योगेंद्र सिंह के साथ हड़ताल पर गये। बिहार में विगत आठ वर्षों से 'संयुक्त संघर्ष' की परंपरा चली आ रही है, इसलिए सभी गुटों से वार्ता कर ७ नवंबर से हमलोग भी हड़ताल पर गये और सरकार को हमसे समझौता करने को मजबूर होना पड़ा।"

सीपीएम के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी में आनेवाले दिनों में संभव है, मतभेद और गहरायें। विधायक अजित सरकार से भी पार्टी सचिव गणेशशंकर विद्यार्थी का छत्तीस का रिश्ता है और केंद्रीय कमेटी के सदस्य नंदकिशोर शुक्ल को भी राज्य सचिवालय से हटा दिया गया है।

भाजपा की मदद: भारतीय जनता पार्टी में प्रांतीय अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी गुट और राष्ट्रीय सचिव कैलाशपति मिश्र के गुटों में भी निरंतर घात-प्रतिघात का खेल जारी है। यों नामधारी को प्रांतीय अध्यक्ष बनवाने में कैलाशपति ने ही अहम भूमिका निभायी थी और आशा की थी कि नामधारी उनकी बात से बाहर नहीं जायेंगे, पर कुछ ही दिनों बाद नामधारी व कैलाशपति में ठन गयी और दोनों में कदम-कदम पर टकराव होने लगे। पार्टी विधायक दल के नेतापद का विवाद हाल ही में हद तक पहुंच गया था। विधानसभा में भाजपा के नेतापद पर सत्यनारायण दुदानी थे। धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र से विधायक दुदानी के चुनाव के विरुद्ध अदालती फैसले के बाद उनकी सदस्यता तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष शिवचंद्र झा ने खतम कर दी। अब दुदानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। इसी चक्कर में सदन में भाजपा विधायक दल के नेता का पद खाली पड़ा था और उपनेता की हैसियत से रामदास राय, सत्यनारायण दुदानी की अनुपस्थिति में कार्यरत थे। पर सत्र के दौरान अचानक भाजपा अध्यक्ष नामधारी ने विधायक जनार्दन यादव को सदन में भाजपा विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। इस पर उपनेता रामदास राय ने नामधारी को चुनौती दी कि भाजपा विधायक दल के नियमों के तहत उन्हें सदन में दल के नेता के मनोनयन का कोई अधिकार नहीं है।

विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ६ फरवरी को नामधारी को तथा ७ फरवरी को रामदास राय को दिल्ली बुलाकर इस विवाद के प्रसंग में बातें कीं और मतभेद दूर करने के लिए कहा। रामदास राय कैलाशपति खेमे के बताये जाते हैं। लिहाजा, घात-प्रतिघात के खेल में नामधारी ने रामदास राय को झटका देने के लिए उन्हीं के स्वजातीय विधायक जनार्दन यादव को सामने कर दिया।

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री

पांच हजार मजदूर निर्णायक लड़ाई में

हक मांगना जुर्म ? : मुख्यमंत्री आवास पर मजदूरों की गिरफ्तारी

रोटी की लड़ाई तो इस देश में सर्वहारा जीवन की नियति है, इसलिए पांच हजार मजदूर अपने पंद्रह हजार नंगे-भूखे, बीवी-बच्चों के साथ सडक पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार को क्या हो गया है जो आंख-कान बंद किये बैठी है ? और सत्तारूढ़ पार्टी क्यों मूक दर्शक बन गयी है—यह जानते हुए कि इससे चुनाव में उसका भट्ठा बैठ सकता है ?

पिछले बीस महीनों से बंद पड़ी सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर अब अपनी लड़ाई को निर्णायक दौर में पहुंचाने पर उतर आये है। सवाई माधोपुर में महीनों आंदोलन चलाने के बाद भूख और गरीबी की मार से त्रस्त मजदूरों ने हाल ही इस लड़ाई के लिए सैकड़ों मील दूर राजधानी जयपुर में डेरा डाल दिया। ढाई हजार मजदूर महिलाओं-बच्चों सहित सिविल लाइंस के बाहर रेलवे फाटक पर धरना देते रहे। जनवरी-फरवरी की कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद चौबीस घंटे सड़क पर जम रहे मजदूरों ने जिस एकता और जिजीविषा का प्रदर्शन किया, वह राजस्थान के इतिहास में अद्भुत है। घटनास्थल पर खानाबदोशों की बस्ती के आ जाने जैसा दृश्य उपस्थित हो गया, इधर महिलाएं काम करती दिखतीं, तो उधर बच्चे खेलते हुए, इधर नौजवान अपने हालात का वर्णन कर आक्रोश प्रकट करते दिखायी देते, तो उधर बूढ़े ऊंघते। एक तरफ सबके लिए सड़क पर ही खाना बनाने की तैयारी, तो दूसरी तरफ पड़ोस में ही विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत के मकान पर भीड़-भाड़ और शोर-शराबे का सिलसिला।

परंतु फैक्ट्री चालू कराने के लिए सरकार से लड़ने के इरादेवाले मजदूरों को एक बार फिर पुलिस से लड़ना पड़ा। धरने के दसवें दिन पुलिस ने धरने पर बैठे मजदूरों, महिलाओं और बच्चों को जबरन उठाकर जयपुर से दूर ले जाकर छोड़ दिया। इससे पूर्व दो माह पहले भी सवाई माधोपुर में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ मजदूरों का संघर्ष हो चुका था, जिसमें भाजपा विधायक डा० किरोड़ीलाल मीणा सहित ७० मजदूर घायल हो गये थे।

राज्य के इतिहास में यह संभवतः पहला मौका है जब फैक्ट्री मजदूरों का आंदोलन राजनीतिक दल द्वारा चलाया जा रहा है और मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियन के नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दूसरी ओर स्थानीय स्तर के आंदोलन की लड़ाई जयपुर की सड़कों पर लड़ी जा रही है तथा आंदोलन प्रांतीय राजनीति के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है।

श्रमिकों का संघर्ष: आंदोलन के दौरान मजदूरों ने राज्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाये। इनमें सवाई माधोपुर में खून भरी बोतलें हाथ में लेकर प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को जबरन चूड़ी पहनाने, घड़ों में सीमेंट भर कर सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर फेंकने, नंगे बच्चों व पेट दिखाकर रोती महिलाओं के प्रदर्शन, रेल रोकने की धमकी से लेकर जयपुर की मुख्य सड़कों पर महिलाओं द्वारा लेटकर खाली पेट का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के घर में जबरन घुसकर नारे लगाने, रेलवे यातायात को रोकने की कोशिश करने तथा दस दिन तक सिविल लाइंस जानेवाली मुख्य सड़क को जाम रखने जैसी घटनाएं शामिल हैं।

आंदोलन की शुरुआत तो सीमेंट फैक्ट्री की तालाबंदी के साथ जून '८७ में ही हो गयी थी, पर तब यह विरोध इस उम्मीद पर कागजों पर ही चलता रहा कि संभवतः सरकार इसे चलाने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठायेगी। अंततः जनवरी '८८ में शहर भाजपा ने एक प्रस्ताव पारित कर सीमेंट फैक्ट्री खुलवाने के लिए किये जा रहे आंदोलन का समर्थन कर दिया। आंदोलन की अगुवाई के लिए भाजपा विधायक डा० किरोड़ीलाल मीणा आगे आ गये। परिणामस्वरूप अप्रैल '८८ में राज्य सरकार ने सीमेंट फैक्ट्री चलाने के लिए नये प्रबंध निदेशक के रूप में इंद्रसिह कावड़िया की नियुक्ति कर दी तथा बैंक को १९७ लाख रु० की गारंटी प्रदान की। परंतु प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण फैक्ट्री नहीं चल सकी और जून '८८ में कावड़िया ने त्यागपत्र दे दिया। संघर्ष समिति के सदस्य केदारनाथ अग्रवाल का दावा है कि इस दौरान फैक्ट्री के स्टॉक से ५ करोड़ रु० का सीमेंट भी बेचा गया, परंतु प्रशासन ने फैक्ट्री चलाने का प्रयास करने के बजाय निजी स्वार्थपूर्ति पर जोर दिया, यहां तक कि करीब ७ करोड़ रु० व्यय हो जाने के बावजूद कोयले की खरीद पर एक पैसा खर्च नहीं किया गया, जबकि बिना कोयले के सीमेंट बन ही नहीं सकता। कोयले की खरीद के लिए मंजूर एकमात्र आर्डर का ड्राफ्ट भी बाद में रद्द करवा दिया गया।

अंततः ३० नवंबर को संघर्ष समिति ने आंदोलन तेज करने की घोषणा कर दी। ६ दिसंबर को जब आंदोलनकारी अपना ज्ञापन देने जिला मुख्यालय पहुंचे, तो जिला प्रशासन के सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में अनुपस्थित थे। ज्ञापन लेने के लिए कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था। इस पर महिलाओं ने रोष में आकर जबरन जिला कलेक्टर के कार्यालय में प्रवेश किया, नारेबाजी की। इसके बाद जब १२ दिसंबर को एक हजार मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था, तो पुलिस ने जुलूस को जबरन रास्ते में ही रोक दिया। इस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गयी, जिसके दौरान भाजपा नेता डा० किरोड़ीलाल मीणा सहित छह दर्जन प्रदर्शनकारी घायल हुए। डा० मीणा के सिर पर चोटें आयीं और उन्हें एक माह तक अस्पताल में भरती रहना पड़ा।

संघर्ष में पुलिसकर्मियों को भी चोटें आयीं।

६ फरवरी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए सवाई माधोपुर के दो हजार मजदूर जयपुर आ धमके। पर कड़े सुरक्षा प्रबंध के कारण वे राजीव गांधी के समक्ष प्रदर्शन नहीं कर सके। इस पर विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत ने घोषणा कर दी कि जब तक मजदूरों की बात नहीं सुनी जायेगी, ये मजदूर जयपुर में डेरा डाले रहेंगे। ७ फरवरी को सुबह ये मजदूर हवाई अड्डे से मार्च करते हुए सिविल लाइंस के फाटक तक पहुंचे और वहां पड़ाव डालकर धरना शुरू कर दिया। परंतु १६ फरवरी को पुलिस ने उन्हें वहां से भी जबरन उठा दिया, आंदोलनकारियों को गाड़ियों में भर-भर कर जयपुर से दूर छोड़ आयी और उनके टेंट वगैरह उठा ले गयी। आंदोलनकारियों के नेता डा० किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर भाजपा विधायकों ने १३ फरवरी से सीमेंट फैक्ट्री खोलने की मांग को लेकर रोजाना गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया, भाजपा नेताओं के अनुसार यह कार्यक्रम फैक्ट्री खुलने तक जारी रहेगा।

२० हजार लोगों का सवाल: असल में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में सवाई माधोपुर की आर्थिक व सामाजिक स्थितियां भी हैं। ६० हजार आबादी के शहर सवाई माधोपुर की अर्थव्यवस्था मूल रूप से खेती, पशुपालन, पत्थर-खदान और सीमेंट फैक्ट्री पर टिकी हुई है। शहर के ही नजदीक लगी सीमेंट फैक्ट्री के पांच हजार मजदूरों को मिलनेवाली ५० लाख रु० प्रतिमाह की तनख्वाह धीरे-धीरे सवाई माधोपुर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गयी है। इसी तरह पांच हजार परिवारों के बीस हजार सदस्यों के सीधे सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े होने के कारण स्थानीय राजनीति में सीमेंट मजदूरों के हितों का विशेष महत्व है।

पिछले सालों में पत्थर खदानों पर धीरे-धीरे 'खान माफिया' का कब्जा होता चला गया। अभयारण्य के लिए वनक्षेत्र को संरक्षित कर देने की घोषणा के बाद चारे के अभाव में पशुपालन भी धीरे-धीरे नष्ट हो गया। पिछले तीन-चार सालों के भीषणतम अकालों की निरंतरता ने जिले की खेती को पूरी तरह चौपट करके रख दिया है। ऐसे में जिले की अर्थव्यवस्था की आशाओं का एकमात्र केंद्र सीमेंट फैक्ट्री ही है। फैक्ट्री के पांच हजार मजदूरों में से अस्सी प्रतिशत बाहर के हैं। उनकी परेशानी यह है कि उनके लिए सवाई माधोपुर में दूर-दूर तक कोई काम नहीं है और बीसियों साल से सवाई माधोपुर में रहने के कारण वे अपनी पुश्तैनी खेती को कभी का बेच चुके हैं, लिहाजा उनके सामने जिंदा रहने के लिए आंदोलन करने और फैक्ट्री खुलने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पिछले उन्नीस महीनों में वे अपनी जमा पूंजी, भविष्यनिधि (प्रॉविडेंट फंड) की राशि व परिचितों से प्राप्त उधार के बल पर इस आशा पर टिके थे कि फैक्ट्री के खुलते ही सब ठीक हो जायेगा। परंतु अब सारे रास्ते बंद देख कर उनके सामने निर्णायक लड़ाई लड़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रह गया। इसी कारण (यह भी संभवतः मजदूर आंदोलन के इतिहास में पहली बार हुआ है) इस आंदोलन में मजदूरों की महिलाओं और बच्चों की भी सक्रिय हिस्सेदारी है।

१९४८ में जयपुर उद्योग के नाम से सवाई माधोपुर में स्थापित करीब १ अरब रु० की लागत का यह एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना सन '७५ से घाटे में चल रहा था। जनता सरकार ने १९७८ में इसे अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रशासनिक अधिकारी को निदेशक मंडल के अध्यक्ष पद पर बिठा दिया। बाद में १९८२-८३ में डीएम प्रसाद के कार्यकाल में यह उद्योग पुनः लाभ की स्थिति में आ गया। इस वर्ष उद्योग ने ४२४ लाख रु० का लाभ कमाया, परंतु १९८५ से यह फिर घाटे में चलने लगा और कार्यशील पूंजी के अभाव में जून, १९८७ में इसमें उत्पादन बंद कर दिया गया। तब से अब तक न तो तालाबंदी की घोषणा ही की गयी और न मजदूरों को नियमित वेतन ही दिया गया। आज इस उद्योग पर करीब ३५ करोड़ रु० की देनदारियां चढ़ गयी हैं। जयपुर उद्योग का 'त्रिशूल' मार्का सीमेंट बाजार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। सीमेंट कारखाने से करीब १०० ट्रक सीमेंट रोज बाहर जाता था जिस कारण इस इलाके में ट्रक व्यवसाय भी खूब पनपा। इसके अलावा सरकार को फैक्ट्री से होनेवाली नियमित आय ४० करोड़ रु० प्रतिवर्ष से अधिक थी तथा ५ हजार मजदूरों के रोजगार सहित पूरे जिले की अर्थव्यवस्था इसी फैक्ट्री पर टिकी रही।

राजनीतिक सबब: राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि राज्य सरकार इस मामले को मानवीय व सामाजिक नजरिये से कम, राजनीतिक चश्मे से ज्यादा देख रही है और आंदोलन की कमान भाजपा के हाथ में देखकर इसका श्रेय भाजपा को देने से कतरा रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जिले में कांग्रेस राजनीति की हालत और भी पतली हो गयी है। पिछले चुनावों में मीणा बहुल सवाई माधोपुर में कांग्रेस-इ के उम्मीदवार को निर्दलीय उम्मीदवार मोतीलाल मीणा के हाथों मात खानी पड़ी थी और अब इस आंदोलन के चलते जिले की राजनीतिक बागडोर किरोड़ीलाल मीणा के हाथों में चली जाने का अंदेशा है। इस पर टिप्पणी करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक भंवरलाल शर्मा कहते हैं, "हमारा दृष्टिकोण राजनीतिक नहीं, मानवीय है, अगर भाजपा कार्यकर्ता किसी घायल को अस्पताल पहुंचाये, तो क्या डाक्टर को इलाज करने से मना कर देना चाहिए? हमारी तो बस एक ही मांग है कि मजदूरों को राहत दी जायें।"

वोट बैंक की खोज: किरोड़ीलाल मीणा

भंवरलाल शर्मा आशंका प्रकट करते हैं, "भविष्य में भूखा मजदूर आंदोलन को अराजकता की ओर भी मोड़ सकता है। तब पार्टी भी कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेगी।" वे दावा करते हैं कि आंदोलन के दौरान ५४ लोग पैसे और समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। वे सरकार की संवेदनहीनता पर टिप्पणी करते हैं, "गद्दी बचाने में व्यस्त मुख्यमंत्री को जब लाखों कर्मचारियों की हड़ताल की ही परवाह नहीं है, तो इन मजदूरों की परवाह वे क्यों करेंगे?" प्रदेश भाजपा मंत्री दामोदर शर्मा कहते हैं, "सरकार यदि चाहती है कि इसे मजदूर खुद सहकारी संगठन बनाकर चलायें, तो वह कम-से-कम छह महीने तक फैक्ट्री को चलाकर मजदूरों को सौंप दे। जयपुर मेटल्स और गुलाबपुरा स्पिनिंग मिलें पहले से ही इसी तरह चल रही हैं।"

संघर्ष समिति के सक्रिय नेता केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, "अगर सरकार एक बार फैक्ट्री चलाकर दे दे, तो हम खुद चला लेंगे। अगर वह सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को फैक्ट्री सौंपना चाहती है तब भी हमें स्वीकार है, यहां तक कि चाहे कोई दूसरा सेठ इसे चलाये, हमें तो मजदूरों की राहत से मतलब है।"

भंवरलाल कहते हैं, "मुख्यमंत्री ने करौली दौरे के दौरान कहा था कि फैक्ट्री चलाने के लिए २०० करोड़ रु० की जरूरत है। बाद में १७ करोड़ रु० की बात की। पर हमारा दावा है कि अगर पुरानी देनदारी माफ की जाये तथा बीमार उद्योग मानकर नियमानुसार रियायत दी जाये, तो मात्र ५ करोड़ रु० की जरूरत होगी। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्जीवन बोर्ड ने भी पांच करोड़ रुपए की सिफारिश की है।"

सरकार ने ११ फरवरी को संघर्ष समिति के नेताओं से बातचीत कर फैक्ट्री को पुनः चालू करने के विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया। परंतु १६ फरवरी को मजदूरों के धरने को जबरन हटवाकर उसने यह संकेत भी दे दिया कि वह उनकी मांगो को अब भी ज्यादा गंभीरता से नही ले रही। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि प्रदेश प्रशासन रोटी की समस्या को राजनीतिक चश्मे से देख रहा है।

—धीरज कुलश्रेष्ठ

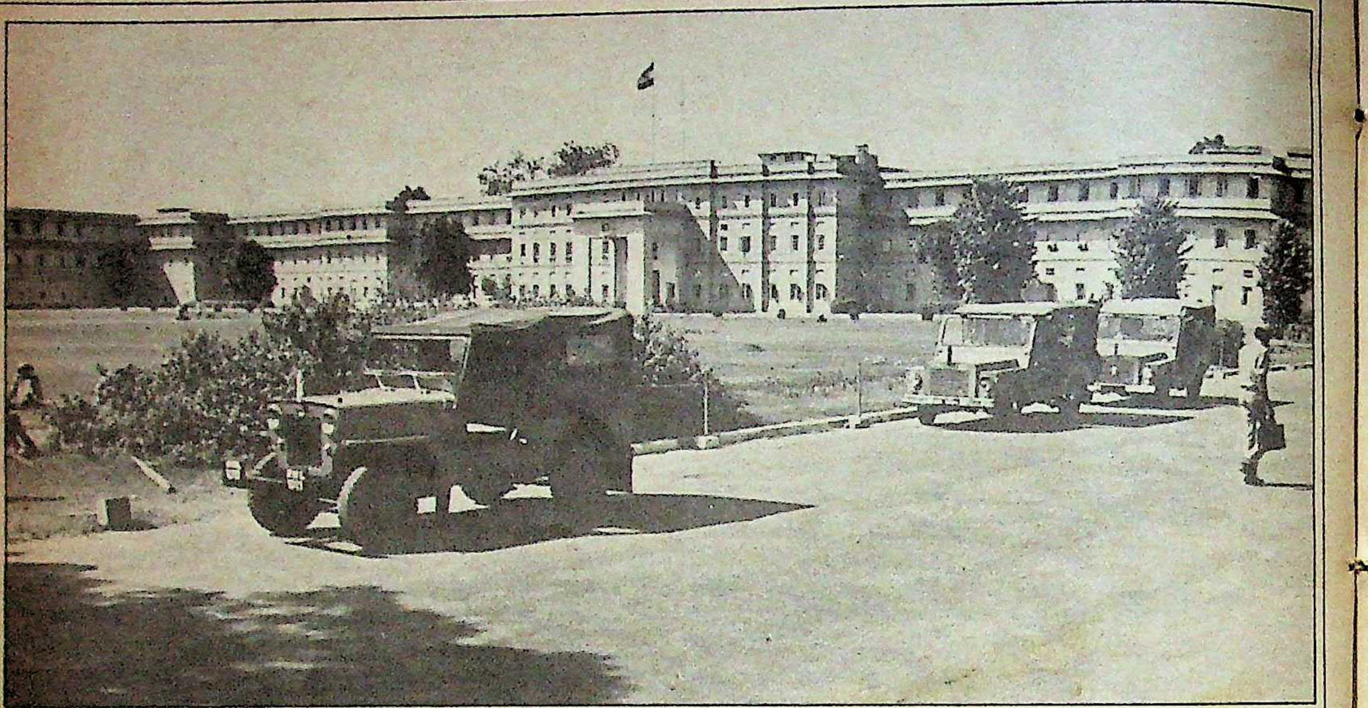

सवर्णों का गढ़ होने का आरोप : जयपुर सचिवालय

रामलाल मीणा

दोषी या जातीय भेदभाव के शिकार ?

राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग के १८ अधिकारियों पर एक जैसे आरोप थे, लेकिन उनमें से तीन अधिकारियों को ही दंडित किया गया। क्या यह संयोग है कि ये तीनों ही अधिकारी अनुसूचित व जनजाति के हैं? तीनों अधिकारी और ४१ विधायक इसे संयोग नहीं मानते, बल्कि इसके पीछे ऊंची जाति के आला अफसरों का द्वेष मानते हैं। यह घातक धारणा किन कारणों से जन्मी है?

"मेरी गलती क्या है? क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी (बाल विकास) जयपुर द्वितीय के नाते मैंने वही किया, जो समाज कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश थे। निदेशक ने ७ मई '८३ से २ जनवरी '८४ तक पांच बार आदेश दिये थे कि मुझे मान्यताप्राप्त उपभोक्ता भंडार से जरूरत की खाद्य सामग्री क्रय करनी है। मैंने तीन जनवरी '८४ एवं ६ जनवरी '८४ को इन्हीं आदेशों के तहत उपभोक्ता भंडारों से सामान खरीदा। समाज कल्याण विभाग द्वारा मार्च माह में बजट पूर्व निश्चित राशि रद्द हो जाने के भय से की गयी इस तरह की भारी खरीद को लेकर समाचार पत्रों में समाचार छपे। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने विभिन्न खरीदारियों की जांच की। इस जांच में तत्कालीन भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक एवं वर्तमान पुलिस महानिदेशक डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया के अनुसार १८ अधिकारी दोषी थे। इनमें से तीन को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने प्राथमिक जांच अप्रमाणित होने के कारण बरी कर दिया। बाकी पंद्रह में से छांट कर उन्हीं तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया है जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के हैं। ऐसी स्थिति में आप संयत अथवा गंभीर आचरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं।"

'माया' को उक्त बयान राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग से निलंबित क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी रामलाल मीणा ने दिया है। दरअसल मीणा ऐसी जनजाति के हैं, जिसे सामंती समाज के कई दौरों से गुजरना पड़ा है। जयपुर की पुरानी राजधानी आमेर से इनके शासक होने का इतिहास जुड़ा है, तो ब्रिटिश और रियासती राज ने इनके अपराधी होने की कथा लिखी है। इस जनजाति को सेवा के हिसाब से रियासतों ने चौकीदार और खेतिहर पातों में बांटा तथा चौकीदार जमात को अपराधी.कौम करार दे दिया। आजादी के बाद बदले हुए माहौल में इस जनजाति ने तेजी से प्रगति की और प्रशासन तथा राजनीति में अपनी निर्णायक स्थिति बनायी। बदली हुई इस स्थिति के बावजूद सवर्ण जमात का सामंती मन इन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है। रामलाल मीणा की तल्खी में यही दर्द छुपा है।

आरोप व निलंबन : प्रकरण की प्रथम सूचना में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक पीडी शर्मा ने १८ अप्रैल '८४ को जांच करने के बाद दर्ज किया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी जयपुर नगर (द्वितीय) रामलाल मीणा ने राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पी-५ (८) वित्त। राजलेअ।७६ दिनांक ३० सितंबर '८३ के अंतर्गत खरीदारी की। इस आदेश के तहत मीणा ने चना, मूंगफली और गुड़ खरीदा। अजमेर उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड से

खरीदी इन वस्तुओं को ये तब तक नही खरीद सकते थे, जब तक कि प्राप्त निविदाओं में उक्त उपभोक्ता भंडार के मूल्य सबसे कम नही होते। शर्मा अपनी जांच में दर्ज करते हैं कि उक्त वर्णित राज्य सरकार के आदेशानुसार किसी सहकारी उपभोक्ता भंडार से ग्रोसरी (किराना) वस्तुएं बिना निविदाएं आमंत्रित किये सरकारी विभाग खरीद सकते हैं, परंतु गुड़, चना, मूंगफली, ग्रोसरी वस्तुएं नही हैं। अपनी जांच में शर्मा आगे दर्ज करते हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी मीणा ने मंडी के भावों से ऊंचे मूल्य पर उक्त वस्तुएं खरीदी। मसलन उन दिनों मंडी में मूंगफली का भाव ८२७ रुपए प्रति क्विटल था, जबकि सहकारी भंडार को ११५० रुपए प्रति क्विटल का मूल्य अदा किया गया। इसी तरह मंडी में चना ३३२ रुपए प्रति क्विटल था, जबकि सहकारी भंडार को ६०० रुपए प्रति क्विटल दिया गया और गुड़ का भाव मंडी में २३१ रुपए प्रति क्विटल था, जबकि भंडार को अदा किया गया ३१० रुपए प्रति क्विटल।

शर्मा की जांच के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी मीणा ने १०० क्विटल मूंगफली, १०० क्विटल चना और ५० क्विटल गुड़ उक्त भाव में खरीद कर ५५ हजार २५० रुपए की आर्थिक हानि जान-बूझकर पहुंचायी। अपर पुलिस अधीक्षक ने मामला अपराध धारा ५ (१) डी (२) पीसीआर उक्त व १६७, १२० भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। मीणा को इसी आरोप के तहत ५ जून '८४ को राजस्थान समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने निलंबित कर दिया।

सफायी में ज्ञापन : मीणा ने इस निलंबन के खिलाफ राजस्थान समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन सचिव एवं आयुक्त केके सक्सेना को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में उनका कहना था कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपनी कथित जांच के बाद मुझे क्रय सामग्री का ५५ हजार रुपए अधिक देने का दोषी ठहराया है, जबकि यह खरीदारी समाज कल्याण विभाग राजस्थान के निदेशक के आदेशानुसार सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सहकारी उपभोक्ता भंडार से की गयी थी। इस खरीदारी में दर तय करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। इस संदर्भ में मीणा ने अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक/५२ अक्तूबर, १९८३ का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक सीएस मुरड़िया को सहकारी उपभोक्ता भंडार जयपुर में बाजार मूल्य से ऊंची दरों पर वस्तुएं होने की बात कही थी। मीणा ने अपने ज्ञापन में दर्ज किया है कि अतिरिक्त निदेशक ने उनके पत्र के जवाब में उनसे पूछा था कि सहकारी भंडारों की मूल्य सूची को चुनौती देनेवाले आप कौन होते हैं? इस ज्ञापन में मीणा ने अपने पर लगे दूसरे आरोप का जिक्र करते हुए लिखा था कि मुझ पर निविदाएं आमंत्रित न करने का आरोप है, जबकि सरकारी भंडार से खरीदारी करते वक्त निविदाएं न आमंत्रित करने का प्रावधान है। उनका बयान है कि यदि वह क्रय कार्यवाही अपराध है, तो इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, क्योंकि मैंने सारी कार्यवाही राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार की है।

न्याय की गुहार : रामलाल मीणा

मीणा अपने पर लगे तीसरे आरोप कि उन्होंने खरीदारी जयपुर उपभोक्ता भंडार से नहीं की, के जवाब में कहते हैं कि १२ व २६ मार्च '८४ के उनके पत्र इस बात के प्रमाण हैं कि जयपुर सहकार उपभोक्ता भंडार को वांछित सामान देने के लिए लिखा गया था.पर उसने पूर्ति में असमर्थता व्यक्त की थी। तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक सीएस मुरड़िया की नीयत पर शक करते हुए वे लिखते हैं कि बजट राशि को रद्द होने से बचाने के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशानुसार अजमेर उपभोक्ता भंडार से खरीदारी के मौखिक आदेश १८ मार्च '८४ को दिये। ज्ञापन में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी पर उनका आरोप था कि जांच अधिकारी ने इन तथ्यों का अवलोकन किया, लेकिन इन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया, परिणामस्वरूप जांच इकतरफा हुई है।

मीणा ने अपने पर लगे चौथे आरोप के संबंध में खुलासा किया है कि अजमेर उपभोक्ता भंडार से क्रय सामग्री को जांच अधिकारी ने ग्रोसरी (किराना) वस्तु नहीं माना है। नियमों में प्रावधान है कि केवल ग्रोसरी (किराना) वस्तुएं ही उपभोक्ता भंडारों से खरीदी जा सकती हैं। इस संदर्भ में मीणा राजस्थान के वित्त विभाग के ३० सितंबर '८३ व निदेशक समाज कल्याण विभाग के ८ सितंबर '८३ के आदेशों का उल्लेख करते हैं, जिनमें गुड़, चने और मूंगफली को ग्रोसरी (किराना) वस्तु माना गया है। मीणा ने अपने ज्ञापन में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी के इस आरोप का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया था कि परियोजना कार्यालय के भंडार से १०० क्विटल मूंगफली के दाने की जगह ११० क्विटल मूंगफली का दाना प्राप्त किया गया जो भुने हुए दाने की जगह कच्चा था। मीणा इसे गलत बताते हुए आरोप लगाते है कि दाना जैसा प्राप्त हुआ था, वैसा ही था। बहरहाल, कोई परिवर्तन हुआ, तो उसके लिए उपभोक्ता भंडार अजमेर जिम्मेदार है।

सरकार पर आरोप : मीणा इसी तरह के ज्ञापन तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री दुलाराम और विभाग के बदलते मंत्रियों तथा सचिवों को इन पंक्तियों के लिखे जाने तक देते रहे हैं, पर नतीजा सिफर रहा है। रामलाल मीणा का अपने ज्ञापनों में आरोप है कि राज्य सरकार और प्रशासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों के प्रति उदार नहीं है। इस संदर्भ में 'माया' ने पाया कि जिस कथित अपराध के लिए मीणा को निलंबित किया गया, उसी अपराध में समाज कल्याण विभाग के और भी १८ अधिकारी शामिल थे। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान के तत्कालीन निदेशक एवं वर्तमान में राज्य पुलिस के महानिदेशक डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) आबिद अली को इस विषय में जानकारी चाहने पर उनके १० मार्च '८६ के पत्र के जवाब में लिखा था, "आपके पत्र संख्या (एफ) (५) (१) (२) संस्थापन पी/जांच/९८५० दिनांक २१-२-८६ के संदर्भ में आपके पत्रांक ५०९४ दिनांक २५-४-८५ के पृष्ठ दो के अनुसार १२ परियोजना अधिकारियों की जांच सौंपी गयी थी, जिनमें कार्य क्षेत्र के अनुसार आठ प्राथमिक जांच क्रम संख्या ८७/८५ से ९४/८५ पंजीकृत की गयी थीं। इनमें कार्य क्षेत्र के अनुसार १८ अधिकारी दोषी पाये गये थे।" पत्र में आगे लिखा गया है कि "जिन तीन अधिकारियों के बारे में जानकारी चाही गयी है, वह इस विभाग के पत्रांक ४३३६ दिनांक २९-११-८५ द्वारा मुख्यमंत्री के सचिव को भेजी जा चुकी है। प्राथमिक जांच ८९/८५, ९२/८५ अप्रमाणित होने के कारण बंद की जा चुकी है।"

गौरतलब बात यह है कि जिन तीन अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने किसी इशारे पर दोषमुक्त किया, उन्होंने गुड़ की खरीद में दो से आठ पैसे तक प्रति किलो गुड़ का मीणा से अधिक मूल्य दिया है। हालांकि चने और मूंगफली के मामले में मीणा ने अधिक मूल्य दिया है। बहरहाल अपराध-अपराध होता है, अगर मीणा को दोषी माना गया, तो निलंबन एवं जांच से बरी किये गये चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और भीलवाड़ा के अधिकारी भी अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। मीणा का आरोप है कि चूंकि इन शहरों के परियोजना अधिकारी एवं उनके सहयोगी सवर्ण जाति के हैं, इसलिए उन्हें कथित अपराध से मुक्त कर दिया गया।

इस संदर्भ में निर्दलीय विधायक मोतीलाल मीणा ने राज्य सरकार से १९८६ में विधानसभा सत्र के दौरान जानकारी चाही, तो उन्हें बताया गया कि निलंबित अधिकारी रामलाल मीणा, मोहनलाल जावा तथा नाथूराम अभय ने क्रमश: जयपुर द्वितीय, जयपुर प्रथम व चाकसू में मूंगफली, चना और गुड़ ऊंची दरों पर खरीदा। जांच के बाद राज्य सरकार को नुकसान का पता चला और इन्हें ५ जून, १९८४ को निलंबित कर दिया गया। अन्य पंद्रह बाल विकास परियोजना अधिकारियों के संबंध में सरकार का जवाब था, "क्रय में हुई शिकायत को ध्यान में रख कर यह जांच की जा रही है कि खरीद में किसी प्रकार की बदनीयती तो नहीं है—प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को आगे की छान-बीन के लिए पत्र क्रमांक ५०९४ दिनाक २५ अप्रैल, ८५ के द्वारा सौंपा गया है।" इन अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के सवाल पर विधायक मीणा को जवाब मिला—"१५ प्रकरणों में से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ६ प्रकरणों में जाच कर उन्हें निरस्त कर दिया गया है। शेष प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जांचाधीन हैं। यदि इनके विरुद्ध किसी भी खरीदारी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी गयी, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।"

इस मामले में गौरतलब यह भी है कि ऊंचे दामों पर खरीद के लिए समाज कल्याण विभाग के १८ परियोजना अधिकारी दोषी करार दिये गये। तीन निलंबित अधिकारियों को छोड़ बाकी पंद्रह अधिकारियों की जांच का काम विभाग ने २५ अप्रैल, १९८५ को राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपा और विभाग ने जल्द ही छह को बरी कर दिया। पर निलंबित अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने तुरंत सीधे छापा मारा। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को केवल निलंबित तीन अधिकारियों का ही ध्यान कैसे आया? 'माया' ने इस संदर्भ में समाज कल्याण विभाग के कागज टटोले, तो १७ नवंबर, १९८४ की समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक एसएन व्यास की कार्यालय टिप्पणी देखने को मिली। यह टिप्पणी व्यास ने मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त उस पत्र के जवाब में लिखी है, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अनुसूचित एवं जनजाति के अधिकारियों को परेशान करने के संबंध में निलंबित अधिकारियों द्वारा प्रेषित ज्ञापन का हवाला था। व्यास के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपने सूत्र से सूचना मिलने पर तीनों अधिकारियों के यहां छापा मारा और पाया कि मूंगफली, गुड़ और चना बहुत ऊंची दरों पर खरीदा गया तथा राज्य सरकार को अनुचित आर्थिक हानि जान-बूझ कर पहुंचायी गयी। वे आगे लिखते हैं, "इस कृत्य के लिए केएन गुप्ता, निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक २०९७ दिनांक ६-६-८४ के द्वारा सचिव महोदय को सूचित करते हुए उपर्युक्त तीनों के निलंबन के निर्देश दिये। फलस्वरूप तीनों अधिकारियों को कार्यालय आदेश दिनांक ५-६-८४ के द्वारा निलंबित कर दिया।"

दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के निदेशक ने ६ जून '८४ को निलंबित करने का परामर्श दिया, जबकि समाज कल्याण विभाग ने परामर्श का अहसास ५ जून '८४ को ही कर निलंबन के आदेश जारी कर दिये। इससे लगता है कि मीणा को उनके पद से निलंबित करने में विभाग के अधिकारियों का कोई स्वार्थ रहा है। इस संबंध में जब मीणा से 'माया' ने जानकारी चाही, तो उनका जवाब था—"खरीद की गयी वस्तुओं को ग्रोसरी (किराना) वस्तुएं न मानने के संबंध में मैंने जांच अधिकारी को अंग्रेजी शब्द कोश देखने को कहा, तो वे नहीं माने। मैंने वित्त विभाग से अपने विभाग को इसका अर्थ भेजनेवाला २१ मई '८४ का पत्र दिखाया, पर जांच अधिकारी ने आरोप बरकरार रखा। जयपुर भंडार सामग्री नहीं देता था और विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक सीएस मुरड़िया बजट से पहले चाहते थे। मैंने निविदाओं के आधार पर १७ मार्च '८४ को सामग्री जयपुर में खरीदने के आदेश चाहे, लेकिन मुरड़िया ने आदेश नही दिये। परिणामस्वरूप अजमेर उपभोक्ता भंडार को १९ मार्च '८४ को सामग्री भेजने के लिए लिखा गया। सामग्री आ गयी, भुगतान हो गया।

गौरतलब बात यह है कि जिन तीन अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने दोषमुक्त किया, उन्होंने गुड़ की खरीद में दो से आठ पैसे तक प्रति किलो गुड़ का मीणा से अधिक मूल्य दिया है । हालांकि चने और मूंगफली के मामले में मीणा ने अधिक मूल्य दिया है। बहरहाल अपराध-अपराध होता है, अगर मीणा को दोषी माना गया, तो चित्तौड़गढ़, बाड़मेर एवं भीलवाड़ा के अधिकारी भी अपराधियों की श्रेणी में आते हैं।

"बहरहाल, जिन ऊंची दरों पर खरीद का आरोप है, उसके संबंध में मैंने अपने निलंबन से पहले ३० सितंबर '८३ को अतिरिक्त निदेशक मुरड़िया से शिकायत की थी। मुरड़िया ने जयपुर के उपहार उपभोक्ता भंडार से उक्त दिनांक को पचपन हजार रुपए की सामग्री क्रय करने की स्वीकृति भेजी थी। इस पत्र के जवाब में मैंने पत्रांक ५२, दिनांक ३ अक्तूबर '८३ को मुरड़िया को अवगत कराया था कि जयपुर का उपभोक्ता भंडार बाजार भाव से ऊंची दरों में सामान दे रहा है, बहरहाल मुरड़िया वहीं से सामान खरीदना चाहते थे। ऐसे में मैंने उपलब्ध भंडार से आदेशानुसार सामान खरीद लिया, तो गलत क्या था?"

रामलाल मीणा का कहना है, "दरअसल, सीएस मुरड़िया और उनके साथी मुझसे खफा रहे हैं। उनके खफा होने की वजह यह है कि निदेशक समाज कल्याण विभाग के पत्रांक एफ (३) पो।... दिनांक २२ मार्च '८४ द्वारा आंगनबाडी कार्यक्रम के लिए खरीदे गये बर्तन व अन्य सामान के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष सीएस मुरड़िया थे तथा उप निदेशक पोषाहार दयाराम गौड़ और मैं उसके सदस्य थे। इस सदर्भ में मैसर्स कट्टा मेटल निवायी को लगभग १३ लाख रुपए का सामान बजट से पहले विभाग को सप्लाई करना था। ३० मार्च '८४ तक यह संस्था केवल एक लाख ४७ हजार ६९० रुपए का सामान ही तैयार कर पायी थी। इस काम का निरीक्षण विभाग के प्रोग्राम अधिकारी एसके चौबीसा, पोषाहार निरीक्षक अनिल मुद्गल के साथ मैंने किया। मुरड़िया ने बाद में मुझ पर दबाव डाला कि कथित माल स्टाक रजिस्टर में जमा कर बिल पास कर दो तथा सरकार को कोई रिपोर्ट न भेजो। मैंने मुरड़िया की बात नहीं मानी और रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। कट्टा मेटल कंपनी को वांछित लाभ नहीं मिला और फिर मुझे फंसाया गया।"

मीणा ने अपने इस आरोप को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के सचिवालय तक में प्रस्तुत अपने हर ज्ञापन में दर्ज किया है। पूर्व ज्ञापनों में पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को राहत न देने पर अनुसूचित एवं जनजाति विरोधी करार दिया गया था। जब वे मुख्यमंत्री पद से हटे, तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को ज्ञापन दिये गये। उनके मंत्रिमंडल की सदस्य श्रीमती कमला भील ने समाज कल्याण राज्यमंत्री के रूप में ही रामलाल मीणा को निर्दोष भी माना है, पर मीणा का निलंबन बरकरार है। 'माया' ने पाया है कि रोहिताश्व कुमार आईपीएस की तरह मीणा के मामले में भी अनुसूचित एवं जनजाति के विधायक अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को परे रख कर उनके बचाव के लिए सामने आये हैं। परियोजना अधिकारी रामलाल मीणा की बहाली के लिए १९ अगस्त, १९८६ को ४१ विधायकों ने हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। विधायकों और सांसदों के ज्ञापनों का यह दौर आज भी जारी है। ज्ञापनों की भाषा से लगता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी व राजनेता राजस्थान शासन एवं सचिवालय को सवर्णों का गढ़ समझने लगे हैं।

—ओम सैनी

सफलता का आधार - सामान्य ज्ञान का भण्डार

सामान्य ज्ञान दर्पण

मौलिक, तर्कयुक्त
वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक तथ्य

विभिन्न
प्रतियोगिता परीक्षाओं
के लिये
उपयोगी

आपकी सफलता का सहयोगी

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक
का सह प्रकाशन

अब कैसे बचेंगे अमर सिंह चौधरी ?

असंतुष्टों को मात देने पर आमादा : मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी

१४ फरवरी '८९ को गांधीनगर (अहमदाबाद) के इंकाई गलियारे में तड़के ही गहमागहमी शुरू हो गयी थी। असंतुष्ट खेमे में चहल-पहल थी और खेमे के तमाम चेहरों पर रौनक छा गयी थी। मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी के विरुद्ध तीन दिन पहले ही असंतुष्टों ने जो नयी मुहिम छेड़ी थी, उसका असर तुरंत दिखलायी पड़ने लगा था। बीमार, बंद पड़ी कपड़ा मिलों को खोलने की मांग लेकर आमरण अनशन पर बैठे, असंतुष्ट इंका सांसद हारूभाई मेहता से मिलनेवालों का दिनभर न केवल तांता लगा रहा, बल्कि उनकी हालत तथा अमरसिंह चौधरी के हठवादी रवैये की खबर थोड़ी-थोड़ी देर पर दिल्ली आलाकमान को पहुंचायी जाती रही, साथ ही चौधरी के विरुद्ध दिल्ली में वातावरण तैयार किया जाता रहा।

परदे के पीछे : जिस समय गांधीनगर में बैठे असंतुष्ट इंकाई मुख्यमंत्री चौधरी के विरुद्ध चक्रव्यूह रच रहे थे, उसी दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रबोध रावल दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी तथा तीन महासचिवों (गुलाम नबी आजाद, शीला कौल व विट्ठल गाडगिल) से मिलकर उन्हें राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। असंतुष्ट गुट का पूरा विश्वास था कि प्रबोध रावल कोई खुशखबरी लेकर ही वापस लौटेंगे। लेकिन बिहार के मामले में अपने हाथ होम कर बैठे आलाकमान तथा प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार गुजरात के मामले में जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा और रुक कर स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी तथा गुजरात के असंतुष्ट नेताओं से बातचीत के बाद जब बिहार के साथ-साथ गुजरात में भी नेतृत्व-परिवर्तन के मामले में शीघ्र ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया, तो गांधीनगर के असंतुष्ट खेमे में उत्साह की लहर दिखाई पड़ने लगी।

लेकिन असंतुष्ट गुटवाले कोई कोर-कसर शेष नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके लिए जरूरी था कि वे मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी के सामने राजनीतिक संकट के साथ-साथ और भी तरीके के दबाव बनाये रखें। चौधरी गुट के एक प्रमुख नेता ने 'माया' को बतलाया, "बीमार या बंद मिलों तथा बेकार पड़े मिल-मजदूरों की समस्या सिर्फ गुजरात की ही नहीं है, समूचे देश की है। गुजरात से कहीं ज्यादा भयावह स्थिति महाराष्ट्र में थी, जहां मिल मालिक बंद पड़ी मिलों की जमीन तक बेचने की पूरी योजना बना चुके थे। ऐसे में जान-बूझकर मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए असंतुष्टों ने सांसद हारूभाई मेहता को अनशन पर बिठा दिया तथा उनके अनशन पर जाने के लिए विवश होने की जिम्मेदारी भी सरकार पर ही थोप दी। हमें खूब पता है कि उन्हें माधव सिंह सोलंकी तथा योगेंद्र मकवाना दिल्ली में बैठ कर हवा दे रहे हैं। दरअसल दोनों, प्रदेश की राजनीति में वापस लौटने की योजना बना रहे हैं। प्रबोध रावल भी गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वे भी परदे के पीछे से असंतुष्टों को पूरी सहायता दे रहे हैं। उन्होंने अपनी दिल्ली-यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो वातावरण तैयार किया, उसकी उन्हें पूरी जानकारी है। आलाकमान अगर असंतुष्टों के सामने झुका , तो गुजरात मे कांग्रेस बेवजह संकट में फंस जायेगी और इसकी जिम्मेदारी सोलंकी पर होगी।"

केंद्र की उदासीनता : इसमें संदेह नहीं की

असंतुष्टों ने अहमदाबाद में बंद पड़ी कई मिलों को खोलने का मामला उठाकर तथा इसके लिए हारूभाई मेहता से अनशन करवाकर चौधरी सरकार के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी है। २० विधायकों ने अपने हस्ताक्षर से एक ज्ञापन १३ फरवरी '८६ को मुख्यमंत्री को देकर मांग की कि अहमदाबाद की मिलों के बंद होने से बेकार हो गये ४० हजार से अधिक मजदूरों को पुन: रोजगार देने के लिए बीमार तथा बंद मिलों को तुरंत खोला जाये, क्योंकि इससे अहमदाबाद के वाणिज्य तथा व्यापार हलकों में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और कांग्रेस बड़ी तेजी से लोकप्रियता खोती जा रही है। ऊपर से देखने में सामान्य लगनेवाला असंतुष्टों का यह ज्ञापन इस कारण विस्फोटक ज्यादा हो सकता है कि इस गंभीर स्थिति की सारी जिम्मेदारी असंतुष्टों ने केंद्र के बजाय राज्य सरकार पर डालते हुए उसे आगामी चुनाव के मुद्दे से जोड़ दिया है।

मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी ने बतलाया कि वे पार्टी विधायकों से राय-मशविरा कर कोई रास्ता निकालेंगे। उन्होंने 'माया' से कहा, "मैंने इस मामले में तुरंत कदम उठाने के लिए उद्योगमंत्री महीदा को निर्देश दे दिया है। लेकिन यह ऐसा मसला नहीं है जिसे तुरत-फुरत हल किया जा सकता है। बहुत सारी कानूनी अड़चनें भी हैं। हमने बीमार तथा बंद मिलों को पुन: चलाने के बारे में केंद्र से बात की है और इसके लिए कारगर योजनाएं भी दी हैं। बेकार मजदूरों के पुनर्वास के लिए सहायता करने के लिए केंद्र ने रजामंदी तो दे दी है, लेकिन बीमार तथा बंद मिलों को पुन: शुरू करने के अनुरोध को फिलहाल मंजूर नहीं किया है। हारूभाई मेहता के अनशन के बारे में भी मैंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री से विस्तार से बातें की हैं।" केंद्र को इस बारे में निर्णय लेने में अभी समय लगेगा। संसद के बजट अधिवेशन के बाद इस बारे में केंद्र कोई कदम उठा सकेगा। असंतुष्ट नेता इस बात को जानते हैं और उन्हें दिल्ली से यह भी खबर मिली है कि फिलहाल कपड़ा मंत्रालय इन मिलों को पुन: खोलने में कोई रुचि नहीं रखता।

द्वंद्व और दावे : मुख्यमंत्री पर दबाव बनाये रखने का मसाला असंतुष्टों को इसलिए भी मिल गया है कि विपक्षी दल मिलों को खोलने का आंदोलन शुरू कर कांग्रेस की लोकप्रियता को खतरे में डाल सकते हैं, जिसका सीधा असर आगामी आम चुनाव पर पड़ेगा। एक असंतुष्ट नेता ने 'माया' को बतलाया, "चौधरी सरकार ने गुजरात में कांग्रेस की साख को खतरे में डाल दिया है। शासन और विधायकों पर उनकी पकड़ एकदम ढीली पड़ गयी है, इससे समूचे राज्य में अव्यवस्था फैल गयी है। मुख्यमंत्री अल्पमत में आ गये हैं, मुश्किल से १४-१५ विधायकों-मंत्रियों का ही उन्हें समर्थन प्राप्त है। इसलिए बेहतर होगा कि वे शालीनता तथा सम्मान के साथ अपने आप ही हट जायें अन्यथा उन्हें जबरन हटाये जाने का अपमान सहना पड़ेगा। हमारे पास १४५ में से ८५ विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, पंचायत चुनावों के खतम होते ही और भी विधायकों के हस्ताक्षर आ जायेंगे। जरूरत पड़ी तो हम असंतुष्ट विधायकों को आलाकमान के पास दिल्ली ले जायेंगे। मुख्यमंत्री पिछली बार भी यह साबित नहीं कर पाये थे कि उनके समर्थक ११० विधायक हैं।"

इसके जवाब में मुख्यमंत्री चौधरी कहते हैं, "असंतुष्ट गुट पार्टी विधायकों पर जबरन दबाव डालकर हस्ताक्षर करवा रहा है। हस्ताक्षर करनेवाले ८५ विधायकों के हस्ताक्षरों की जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि उनमें से कितने सही हैं। हमने इस बारे में प्रधानमंत्री को सूचित कर दिया है और यह भी बतला दिया है कि इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। हमें असंतुष्टों की गतिविधियों से कोई परेशानी नहीं है। चुनाव के निकट आते ही उनकी गतिविधियां अपने आप महत्वहीन हो जायेंगी। पार्टी में कलह से निबटने के लिए हमने जो प्रयास किये हैं, उनकी सराहना हाईकमान ने की है।" एक प्रमुख मंत्री द्वारा उन्हें सत्ताच्युत किये जाने की साजिश चलायी जाने की बात चौधरी ने मुस्करा कर बतलायी, "मैं इस मामले पर विशेष रूप से नजर रख रहा हूं। प्रधानमंत्री तथा हाईकमान को भी इसकी पूरी सूचना दे दी है।"

माधव सिंह सोलंकी

माधव सिंह सोलंकी तथा योगेंद्र मकवाना दिल्ली में बैठकर हवा दे रहे हैं। दरअसल दोनों, प्रदेश की राजनीति में वापस लौटने की योजना बना रहे हैं। प्रबोध रावल भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए वे भी परदे के पीछे से असंतुष्टों को पूरी सहायता दे रहे हैं।

लड़ाई सड़क पर : असंतुष्ट गुट के नेता मुख्यमंत्री पर अपने टेलीफोन टेप किये जाने के आरोप शुरू से ही लगाते रहे। १४ फरवरी को भाजपा विधायक अशोक भट्ट ने भी सदन में खुला आरोप लगाया कि एक मंत्री (जो असंतुष्ट गुट से मिलकर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुहिम चला रहे हैं) का टेलीफोन निरंतर टेप किया जाता है और इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री को दी जाती है। यद्यपि मुख्यमंत्री ने तुरंत अशोक भट्ट को आरोप सिद्ध करने की चुनौती दी, लेकिन इस बात का खुलासा कभी नहीं किया कि उक्त मंत्री की गतिविधियों पर वे किस तरह से नजर रखे हुए हैं।

चौधरी के विरोधी और समर्थक गुटों की लड़ाई अब एक तरह से सड़क पर आ गयी है। पिछले दिनों गुजरात कांग्रेस विधायक दल की बैठक की शुरुआत ही हाथापाई से हुई थी जिसमें बेचारा माइक लगानेवाला बुरी तरह से घायल हो गया था। इस हाथापाई का नजारा देख रहे मंत्रियों ने इस हद तक तटस्थता का रुख अपना लिया था कि असंतुष्ट गुट के दिगंत ओझा, मुलराज, परमार भक्त, जीतूशाह गांधवी, रमेश ठाकुर, आर नरेंद्र रावल, घनश्याम ठक्कर तथा श्रीमती चंद्रबेन श्रीमाली के आक्रामक प्रहारों से मुख्यमंत्री की रक्षा के लिए आगे आने की भी जरूरत नहीं समझी। मुख्यमंत्री के विरुद्ध जब असंतुष्टों ने खुले बयान नियमित रूप से पत्रकारों को देने शुरू किये तब भी कोई मंत्री खंडन या स्पष्टीकरण के लिए आगे नहीं आया। इस पर एक असंतुष्ट नेता ने 'माया' को बतलाया, "दरअसल गिनेचुनों को छोड़कर अधिकांश मंत्री भी उनसे नाराज और हमारे साथ हैं। हमने हाईकमान को साफ कह दिया है कि अगर चौधरी को हटाने का निर्णय तुरंत नहीं लिया गया, तो गुजरात भी तमिलनाडु में बदल जायेगा।" एक अन्य असंतुष्ट सांसद आर वलीउल्वा ने बतलाया, "मैंने प्रधानमंत्री को तार भेजकर चौधरी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। चौधरी को असंतुष्टों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करने का हक ही नहीं रह गया है, क्योंकि वे चिमनभाई मेहता तथा सहदेव चौधरी (दोनों इंका से निष्कासित) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"

फरवरी के तीसरे सप्ताह में दिगंत ओझा तथा जीतूशाह के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे १२ असंतुष्ट विधायकों के दल ने अब नयी पैंतरेबाजी अपना कर गुजरात की लड़ाई गांधीनगर के साथ-साथ दिल्ली में भी शुरू कर दी है। यह गुट जीनाभाई दारजी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अब देखना यह है कि इस बारे में माधव सिंह सोलंकी क्या कदम उठाते हैं।

—रवींद्र श्रीवास्तव, अहमदाबाद से

गति दे

प्रीमा पर 106 शब्द प्रति मिनट की सुपर स्पीड. नैशनल स्पीड टाइपिंग चैम्पियनशिप में. हल्के स्पर्श का कमाल.

प्रीमा पर 123 घंटे लगातार टाइपिंग. गिनिस बुक में शानदार स्थान. **प्रीमा** के टिकाऊ होने व बेशिकायत काम का प्रमाण.

प्रीमा में कितनी ही अनोखी विशेषताएं, जैसे पन्ना-समाप्त-सूचक और खड़ी-रेखा सुविधा. साथ ही 15 टाइपस्टाइल, ज्यादातर भारतीय और चुनी हुई विदेशी भाषाएं उपलब्ध.

प्रीमा के लिए देश-भर में फैला लाजवाब बिक्री-बाद-सेवा का जाल.

गोदरेज **प्रीमा**. भारत का नंबर एक टाइपराइटर. इसमें आश्चर्य कैसा !

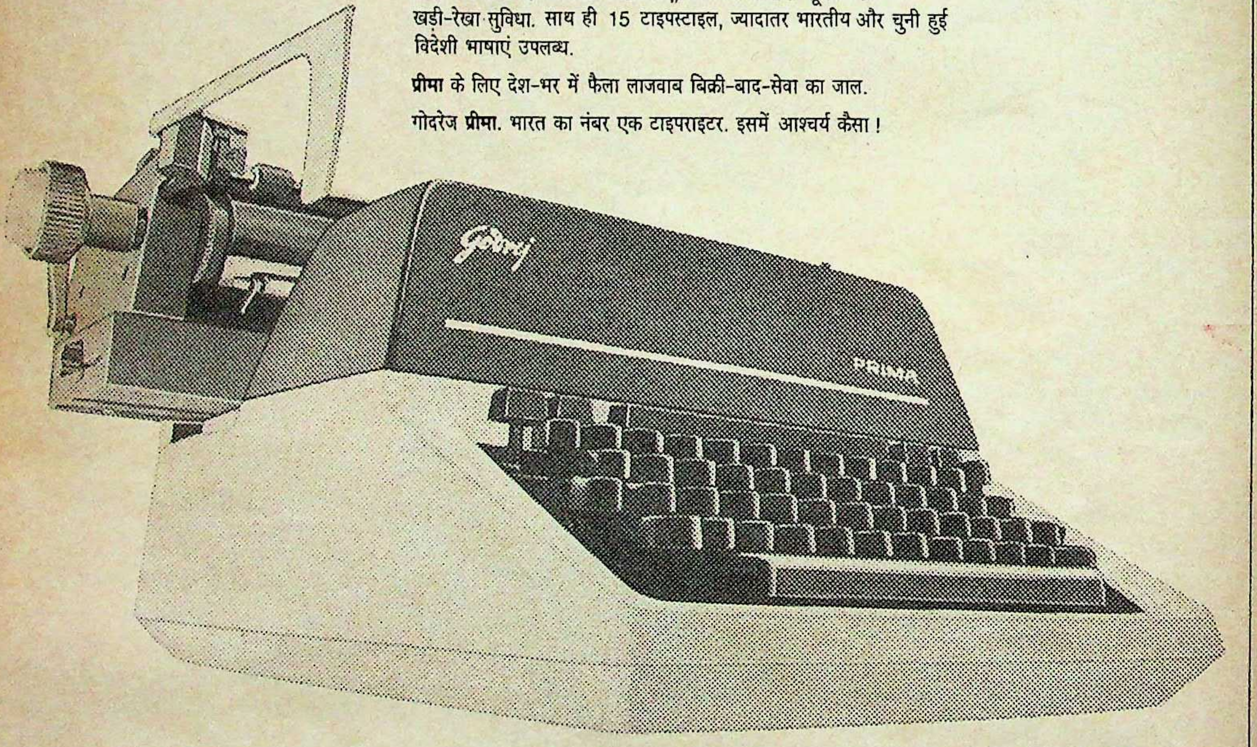

खूब चले

Godrej®
PRIMA
भारत का प्रमुख टाइपराइटर

ULKA-11755-HIN

बेरोजगारी

खाड़ी देशों की ओर भागते लोग

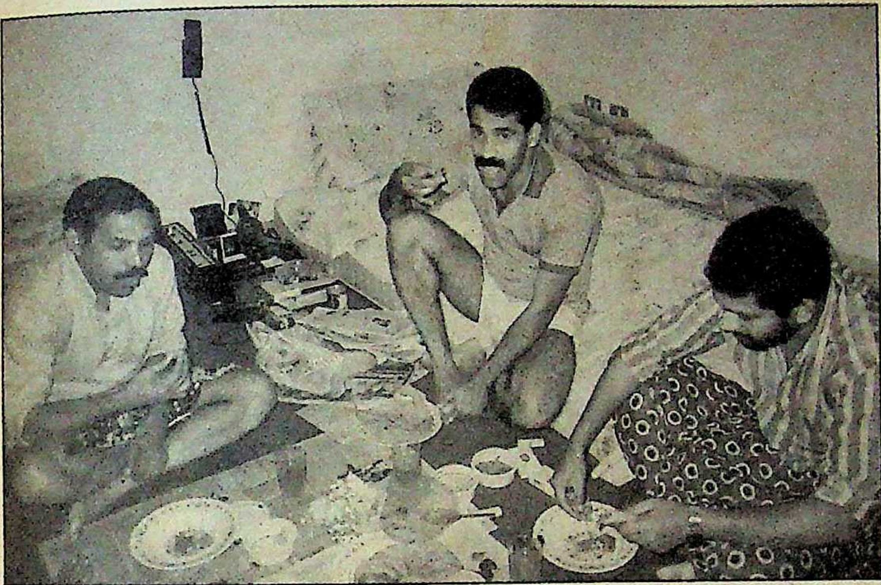

मुफ़लिसी से मुक्ति : खाड़ी के एक देश में केरलवासी

विजू अब्राहम रियाद स्थित एक बड़ी दुकान में सेल्समैन का काम करते हैं। थामस एंथनी दिन में दरबान का काम करते हैं और रात में कारें धोकर थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। केपी प्रेमनाथ राबुआ बाजार में सब्जी बेचते हैं। इसी तरह के मोहम्मद इस्माइल एक गैराज में सुबह आठ बजे से रात ग्यारह बजे तक मेहनत करते हैं। रियाद में तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे ये लोग प्रतिमाह ४००० रुपए से अधिक कमा लेंते हैं। इन्हें इस बात की खुशी है कि भले इन्हें परदेश रहना पड रहा है, किंतु इनके समक्ष रोजगार की समस्या तो नहीं है। फिर इतने सालों रियाद में काम करके इन लोगों ने इतना तो कमा ही लिया है कि यदि इन सबको रियाद छोड़ना भी पड़ा, तो इनके परिवारजन भूखे नहीं रहेंगे। जाहिर है, ये लोग भी अपना देश, अपना शहर, अपना गांव छोड़कर यदि इतनी दूर न गये होते, तो क्या ये इतने खुशहाल हो सकते थे? फिर ये सभी तो उस राज्य के रहनेवाले हैं, जहां आज भी लाखों लोग रोजगार के लिए सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं और निराश होकर घर बैठ जाते हैं या एक दिन जब उन लाखों में से कुछ यह मान लेते हैं कि उनके लिए सभी दरवाजे बंद हो गये हैं, तो ईमानदारी से कमाकर जीवन गुजारने की इच्छा को त्याग कर बेईमानी को गले लगा लेते हैं।

खाड़ी देशों का सहारा : अब्राहम, एंथनी, प्रेमनाथ और इस्माइल केरल के निवासी हैं। ये लोग उन ३,९०,००० भारतीयों में से हैं, जो सऊदी अरब जाकर कमाने पर मजबूर हैं। सचाई तो यह है कि खाड़ी देशों में रोजगार से लगे लगभग ४ लाख भारतीयों में अधिकांश केरल के ही हैं। देश छोड़कर खाड़ी देशों की ओर भागनेवाले बेरोजगारों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। आज भी स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में केरलवासी रियाद, जद्दा तथा दूसरे शहरों में नौकरी करने के उद्देश्य से निरंतर भारत छोड़ रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार देश छोड़कर रोजगार के लिए अन्यत्र जानेवाले लोगों में बहुतेरे ऐसे हैं, जिन्हें मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी जमीन-जायदाद को बंधक रखना पड़ता है। जाहिर है, सिवाय इसके वे और कर भी क्या सकते हैं? केरल में दिन-प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार काबू नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में बेरोजगार रहकर मारे-मारे फिरने से बेहतर तो विदेश जाकर रोजी-रोटी कमाना ही है।

दूसरी ओर केरल सरकार खाड़ी देशों में मंदी आने का बहाना लेकर बड़ी तादाद में केरलवासियों के खाड़ी देशों से लौटने का ढिंढोरा पीट रही है। सरकारी सूत्रों का तर्क है कि केरल में रोजगार के लिए हाहाकार मचने का कारण खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में केरल लौटे केरलवासी ही हैं। सूत्रों का कहना है कि यदि खाड़ी देशों में मंदी न आयी होती, तो केरल में स्थिति इतनी चिंताजनक न होती। इस संबंध में केरल सरकार ने पिछले साल लौटनेवालों का एक अनुमान पेश किया था, जिसके अनुसार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और बहरीन से पिछले साल के अंत तक लौटनेवालों की संख्या ९००० थी। सरकार का दावा है कि उपर्युक्त संख्या का ७० फीसदी भाग गत तीन वर्षों के दौरान केरल लौटा है। इसी के अनुसार १९७०-७५ के बीच सिर्फ ४३२ लोग लौटे थे और अकेले १९८४ में १०,००० लोगों की वापसी दर्ज की गयी थी।

असमर्थ सरकार : मजे की बात यह है कि बेरोजगारी पर काबू न कर पाने की असमर्थता पर नकाब डालने के उद्देश्य से सरकार केरल वापस आनेवालों की संख्या का बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार तो करती है, किंतु इस विषय में यह अनुमान पेश करने से सकुचाती है कि प्रतिवर्ष रोजगार की तलाश में कितने केरलवासी केरल छोड़ रहे हैं? जाहिर है, सरकार यदि बेरोजगारी से ऊब कर केरल छोड़नेवालों की तादाद भी बताना शुरू कर देगी, तो उसकी अकुशलता और असमर्थता कैसे छिपेगी? जबकि तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि अनुबंध की समाप्ति के कारण प्रतिवर्ष जितने लोग केरल लौट रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा लोग नये अनुबंधों के तहत खाड़ी देश जा रहे हैं। इस संबंध में रियाद स्थित भारतीय दूतावास के श्रम सचिव कृष्ण कुमार बताते हैं, "मेरे कार्यालय में प्रति महीने सत्यापित होनेवाले वीसा की संख्या बढ़कर ४०० तक पहुंच गयी है। सत्यापित होनेवाले वीसा कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल मजदूरों के होते हैं। हमारे पास डाक्टर, इजीनियर और प्रशासकों की संख्या उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें वीसा सत्यापित कराने की जरूरत नहीं होती।" यही नहीं, दूतावास के ही एक दूसरे अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ 'माया' से कहा, "केरल सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है, वे सही नहीं। फिर सरकार सिर्फ लौटनेवालों का जिक्र करती है, हर महीने केरल छोड़नेवालों का नहीं। यदि यह मान लिया जाये कि गत वर्ष लगभग ९००० लोग केरल लौटे, तो यह भी तो सच है कि पिछले कुछ महीनों में लगभग ९००० या इससे कुछ ज्यादा लोग खाड़ी देश पहुंचे हैं।" दूतावास के एक अन्य सूत्र के अनुसार पिछले कुछ महीनों में रोजगार के लिए खाड़ी देश पहुंचे लोगों में ज्यादा लोग नये हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से कम वेतन पर पुन: अनुबंध हासिल कर पहुंचे हैं। इस संबंध में एक मिसाल पेश करते हुए दूतावास के एक अधिकारी बताते हैं कि अनुबंध समाप्त होने से पहले इंजीनियर केजी जार्ज दम्माम की एक कंपनी में प्रतिमाह २०,००० रुपए पाते थे। छह महीने के बाद जब वे पुन: नौकरी के लिए गये, तो उन्हें मात्र १०,००० रुपए पर ही काम करने को तैयार होना पड़ा। अधिकारी का कहना है कि जार्ज तो सिर्फ मिसाल हैं। दोबारा खाड़ी देश जानेवाले लोगों में अधिकांश ऐसे ही हैं जो पहले से कम वेतन पर काम कर रहे हैं। खाड़ी देशों के लिए भर्ती करनेवाले बंबई के एक एजेंट टीपी जोसफ 'माया' से कहते हैं, "खाड़ी देशों से लौटने और वहां जानेवालों की संख्या कमोबेश बराबर ही रही है।" जोसफ बतलाते हैं कि बहरीन में स्थिति यह है कि वहां के स्थानीय ३५०० लोग

जवाहरलाल नेहरू जन्मशती
JAWAHARLAL NEHRU CENTENARY
1889 1989

सिर्फ़ प्यार ही नहीं चुका सकता इनकी दवाओं के बिल.

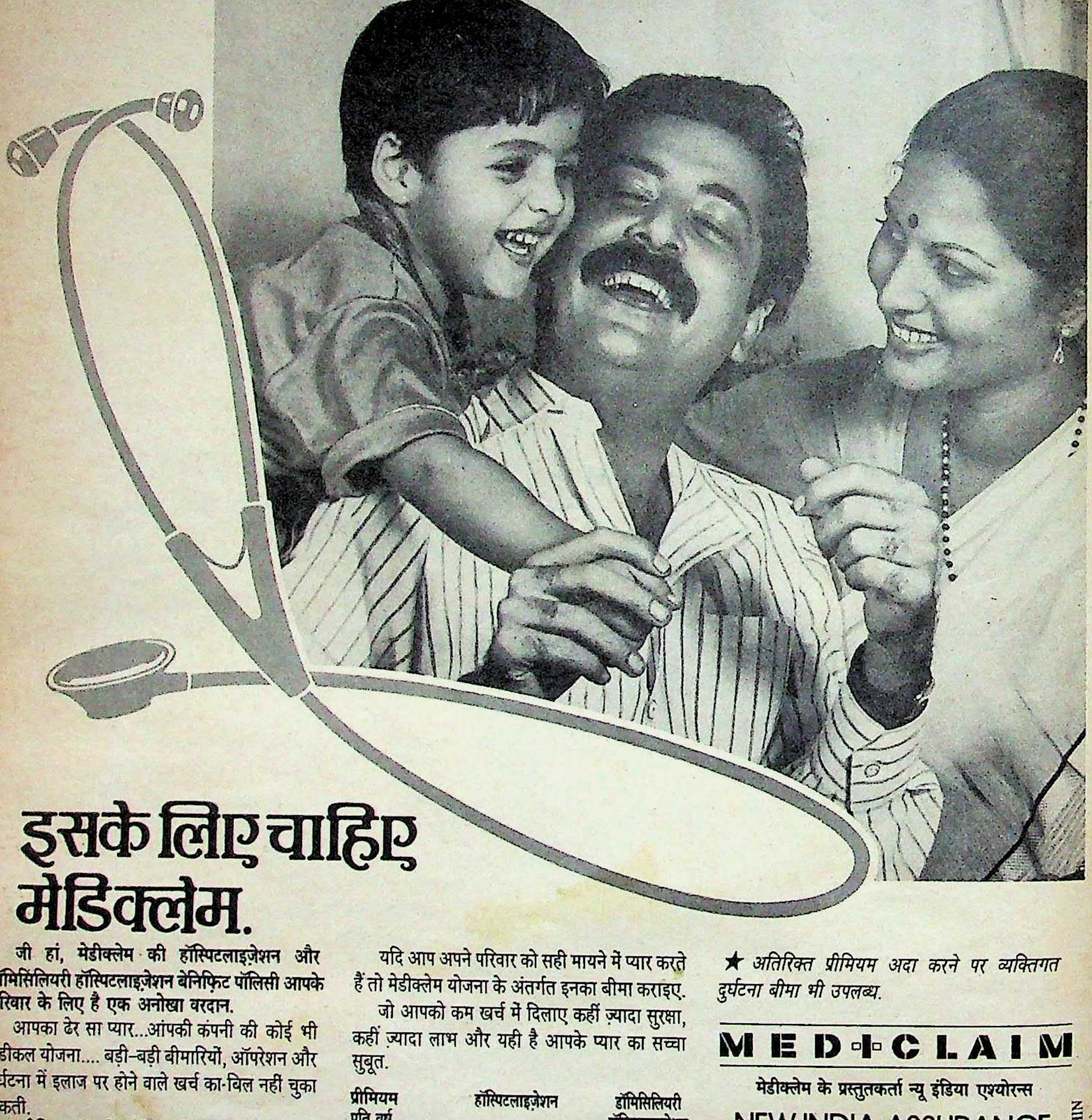

इसके लिए चाहिए मेडिक्लेम.

जी हां, मेडीक्लेम की हॉस्पिटलाइज़ेशन और डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन बेनिफ़िट पॉलिसी आपके परिवार के लिए है एक अनोखा वरदान.

आपका ढेर सा प्यार...आंपकी कंपनी की कोई भी मेडीकल योजना.... बड़ी-बड़ी बीमारियों, ऑपरेशन और दुर्घटना में इलाज पर होने वाले खर्च का-बिल नहीं चुका सकती.

इसीलिए आपको चाहिए मेडीक्लेम. मेडीक्लेम के ज़रिए आप कई तरह के चिकित्सा लाभ हासिल कर सकते हैं– वह भी आपकी आवश्यकता, आपकी ज़रूरतों के अनुरूप.

यहां तक कि आप घर पर रहकर इलाज करने का खर्च भी पा सकते हैं.

साथ ही आप पारिवारिक-छूट और करों में छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.

यदि आप अपने परिवार को सही मायने में प्यार करते हैं तो मेडीक्लेम योजना के अंतर्गत इनका बीमा कराइए.

जो आपको कम खर्च में दिलाए कहीं ज़्यादा सुरक्षा, कहीं ज़्यादा लाभ और यही है आपके प्यार का सच्चा सुबूत.

प्रीमियम प्रति वर्ष रु.	हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.	डॉमिसिलियरी हॉस्पिटलाइज़ेशन रु.
२००	१०,५००	३,१००
२५०	१७,६००	–
३५०	२५,५००	–
६०० *	३७,७५०	५,२५०
८४० *	५२,७५०	७,४००
१,३०० *	८२,५००	११,५००

आयु सीमा ५ से ७० वर्ष

★ *अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध.*

MEDICLAIM

मेडीक्लेम के प्रस्तुतकर्ता न्यू इंडिया एश्योरन्स

NEW INDIA ASSURANCE

A subsidiary of the General Insurance Corpn of India

ख़तरे का कोई भी नाम....
बीमा करना हमारा काम.

CONTOUR ADS-NIA-278B/87 R-HIN

आज भी बेरोजगार हैं, लेकिन प्रतिमाह ४०० भारतीय बहरीन काम करने पहुंच रहे हैं, जिनमें अधिकांश केरल के हैं। रियाद के अल-शरीफ ट्रेडिंग एंड कंट्रैक्टिंग इस्टैबलिशमेंट के प्रबंधक एम के गोपीनाथ कहते हैं, "खाड़ी देशों में कम वेतन पर भी रोजगार उपलब्ध होने का केरलवासियों को एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि अगर वे केरल में होते, तो शायद बेरोजगार ही रहते।

पेंग मारती बेरोजगारी : गोपीनाथ की बात किसी हद तक सही भी है। २.७५ करोड की आबादी वाले केरल में करीब ३० लाख लोग आज भी बेरोजगार हैं। १९८७ में २,५०,००० से अधिक लोगों ने रोजगार कार्यालय में अपने नाम दर्ज कराये थे। इनमें से ३२,००० लोग तकनीकी रूप से योग्य, ४४४३ इंजीनियर, १५३२ डाक्टर और २९३ कृषि स्नातक थे। १९८६ में पंजीकृत होनेवाले २,५०,००० लोगों में से सिर्फ १५६०७ लोगों को ही रोजगार मिला। १९८७ के पहले छह महीनों में रोजगार पानेवालों की संख्या मात्र ८००८ थी।

केरल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी का कारण वहां नये उद्योगों का न खुलना भी है। स्थिति यह है कि मजदूर अशांति से ऐसा डर व्याप्त है कि कोई भी उद्योगपति केरल में पूंजीनिवेश करना नहीं चाहता। हालात इतने बिगड़ गये हैं कि राज्य सरकार द्वारा बड़े कर्जों की पेशकश के बावजूद समृद्ध केरलवासी भी केरल में उद्योग लगाने से हिचकते हैं। उत्तर केरल में कालमेट्टा के पास फलों के रस को डिब्बाबंद करने के प्लांट के मालिक टी रामदास इस संबंध में बताते हैं, "मेरी फैक्टरी में अभी तक तो कोई संकट नही आया, लेकिन मैं भयभीत तो रहता ही हूं। पूरा माहौल तनावपूर्ण है। कोई नहीं जानता कि कब सब कुछ उलट-पलट जाये।"

मोहन अमीन का अनुभव तो बहुत ही बुरा है। करीब दो साल पहले अमीन पुराने जहाजों को तोड़नेवाली कपनी वैचर रीसाइक्लर्स की एक शाखा का काम देखने के लिए कोचीन गये। बंबई मुख्यालय वाली इस कंपनी ने ६५ लाख रुपए से यह शाखा खोली थी जहां पहले दिन से ही झंझट शुरू हो गयी। स्थानीय मजदूर संगठनों ने विरोध किया कि अमीन बंबई से कुशल कारीगरों को क्यों लाये? जबकि सचाई यह थी कि वैसे कारीगर कोचीन में उपलब्ध नहीं थे। जब इंका से जुड़ी इंटक और माकपा से जुड़े मजदूर संगठनों ने तोड़फोड़ की कोशिश की, तो विवश होकर अमीन को उनके २० लोगों को नौकरी देनी पड़ी। पर ये तमाम लोग किसी काम के नहीं थे।

उग्र संघवाद : यहां पर यह कहना गलत न होगा कि मजदूरों के उग्र संघवाद के कारण भी केरल की अर्थव्यवस्था तेजी से खराब हुई है। इंका के पांच वर्षों के शासनकाल में केरल में ४० से कम बड़े उद्यम लगे। इस अवधि में ५० से कम लोगों ने ही लघु उद्योग खोले। राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां तो आज भी भारी नुकसान में चल रही हैं। मार्च १९८७ तक राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की ४१ इकाइयों ने—जिनमें १४४.५४ करोड़ की पूंजी लगी है—१३२.८१ करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था।

मजदूरों के इसी रुख के कारण मुनाफे में चल रही अनेक कंपनियों को घाटा होने लगा, तभी वे अपना कारोबार पड़ोसी राज्यों में ले जाने को बाध्य हुई थीं। इस संदर्भ में कालीकट स्थित बिड़ला समूह की कंपनी ग्वालियर रेयान का उदाहरण पेश किया जा सकता है। इस कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन और बोनस देने के बावजूद पिछले दशक में यहां लंबी हड़तालें हुईं। नतीजतन बिड़ला घराने के लोगों को विवश होकर यह प्लांट बंद करना पड़ा और सैकड़ों मजदूर परिवारों के लिए भारी मुश्किल आ गयी। परेशान होकर १४ मजदूरों ने आत्महत्या कर ली थी। फिर भी प्रबंधक झुके नहीं। पिछले साल नयनार सरकार की कोशिशों के फलस्वरूप बिड़ला परिवार इस प्लांट को फिर से चालू करने पर सहमत हुआ है। स्थिति यह थी कि तंगहाल मजदूर किसी भी हालत में अपनी नौकरी वापस पाना चाहते थे। क्योंकि खाड़ी देशों में रोजगार पाने का सौभाग्य सभी केरलवासियों को तो प्राप्त नहीं होता। राज्य के २३५ कालेजों से स्नातक होनेवाले हजारों नौजवान अपने भाग्य से बंधे हैं और नाउम्मीदी में जीने को अभिशप्त हैं। स्थिति यह है कि लोक सेवा आयोग की १९८७ की परीक्षा में ऊंचे स्थान पानेवाले लोगों को भी अभी तक काम नहीं मिल पाया है।

> **खाड़ी पहुंच गये लोग अपने भाग्य को सराह रहे हैं। क्योंकि यदि उनके भाग्य ने भी साथ न दिया होता, तो आज उन्हें भी केरल की दिन-पर-दिन बिगड़ती स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता।**

मजे की बात तो यह है कि जहां एक ओर रोजगार की तलाश में लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, वहीं कुछ ऊंचे पद वाली नौकरियों के लिए रिश्वत के रूप में बड़ी रकम देकर धनवान अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिनके पास रुपया नहीं वे तो लाख डिग्री और अनुभव वाले क्यों न हों, उन्हें कोई पूछता नहीं। रबर और चाय बागानों के मालिकों की संतानों को ही यह सब नसीब होता है जो मौज मजे के लिए ही काम करते हैं। फिर मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाहों तक ऐसे परिवारों की ही पहुंच है। आम आदमी तो इन लोगों से मिलने को तरसता है। सूत्रों ने 'माया' को बताया कि लेक्चरर की नौकरी १,००००० रुपए में मिलती है और पुलिस इंस्पेक्टर पद के लिए ७५,००० रुपए देने होते हैं। पैसा देकर रोजगार पाने के 'रिवाज' के कारण क्विलोन के एमए पास केएम मैथ्यू जैसे नौजवानों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें मामूली या किसी भी तरह के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। बंबई आने के बाद मैथ्यू कुछ महीनों तक तो बेरोजगार रहे, पर बाद में उन्होंने एक रेस्तरां में चीनी और भारतीय व्यंजन बनाना सीख लिया और बांबे हाई के एक आयल रिग में रसोइये की नौकरी कर ली।

इसी तरह बंबई के एंटोप हिल पर स्थित सीजीएस क्वार्टर्स में पहुंचने पर भी केरल की बेरोजगारी के दर्शन होते हैं। यहां के सस्ते फ्लैटों में हजारों केरलवासी भरे पड़े हैं। इनमें से कुछ तो खाड़ी देश पहुंचने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अधिकांश बेहद कम वेतन पर काम करके जैसे-तैसे गुजर कर रहे हैं। सीपीडब्ल्यूडी में बिजली मिस्त्री का काम करनेवाले पीके थामस ५ साल काम करने के बाद भी प्रति माह ८०० रुपए नहीं कमा पाते। यहीं मुवाटुपुषा के मांसी वर्गीज भी रहते हैं। वह तीन साल से टाइपिस्ट के रूप में प्रति माह ६०० रुपए ही कमा रहे हैं। उनका कहना है, "मैं तो ऊब गया हूं। मैं अपने मां-बाप के पास केरल वापस जाना चाहता हूं। लेकिन वहां मैं करूंगा क्या? वहां तो मेरी और खराबी होगी। यदि यही स्थिति बनी रही, तो मैं जल्दी ही पागल हो जाऊंगा।"

सरकार लाचार है : मजदूरों में उग्र संघवाद लानेवाली पार्टी माकपा—जो सत्ता से ५ वर्ष बाहर रही है—के मुख्यमंत्री ईके नयनार बेरोजगारी की इस स्थिति को लेकर मुश्किल में फंसे हैं। उद्योग मंत्री श्रीमती केआर गौरी केरल में पूंजीनिवेश करने के लिए उद्योगपतियों से आग्रह कर रही हैं और बेहतर सुविधाओं और हड़ताल पर रोक लगाने में मदद करने का आश्वासन रोज दे रही हैं। लेकिन उनके आश्वासनों पर बहुत कम लोग भरोसा कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार—जिसके पास अपने कुछ विभागों का टेलीफोन बिल भरने तक का पैसा भी नहीं है—प्रतिवर्ष राज्य के १,९४,००० बेरोजगारों को ६.७ करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने को विवश है।

ऐसी स्थिति से पीछा छुड़ाकर जो लोग खाड़ी देश पहुंच गये हैं, वे सचमुच भाग्यशाली हैं। कुछ वर्ष पहले की तुलना में वेतन भले ही कम हो गया है, फिर भी वे केरल में काम कर रहे साधारण अधिकारियों से अधिक ही कमा लेते हैं। आज स्थिति यह है कि केरल में बेरोजगारों की संख्या बढ़ते देखकर खाड़ी पहुंच गये लोग अपने भाग्य को सराह रहे हैं। क्योंकि यदि उनके भाग्य ने भी साथ न दिया होता, तो आज उन्हें भी केरल की दिन-पर-दिन बिगड़ती स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता जिसका लाखों केरलवासी सामना कर रहे हैं।

—जॉय राफेल,
कालीकट और रियाद से,

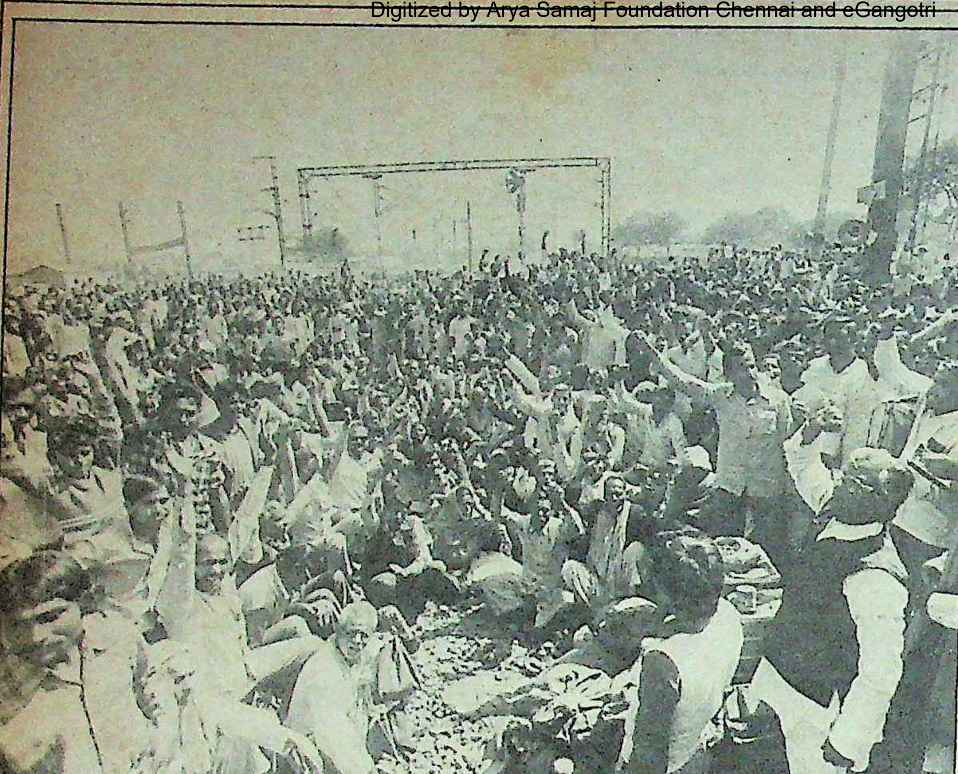

छाया : मनमोहन शर्मा

सर्वहारा का जेहाद : जुही रेलवे पुल पर कपड़ा मजदूरों का ऐतिहासिक जमाव

कानपुर में १०७ घंटे का रेल जाम

सरकार को झुकना ही पड़ा !

कानपुर के ३५ हजार कपड़ा मजदूरों ने १०७ घंटे तक रेल जाम करके नारायण दत्त तिवारी की सरकार को बाध्य कर दिया कि वह विवादास्पद पाण्डेय अवार्ड को बिना शर्त वापस ले ले। कपड़ा मिल मजदूरों के धरने के कारण १०३ यात्री और माल गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। कानपुर के कपड़ा मिल मालिकों के झगड़े की शुरुआत १९३८ से होती है। प्रति पांच वर्ष बाद मजदूर अपने तेवर दिखाते आ रहे हैं। पर इस बार २२ फरवरी से जो रेल जाम आंदोलन शुरू हुआ, उसका बीज अक्तूबर, १९८५ में बोया गया था। उस वर्ष मजदूरों ने वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल का नोटिस दिया था। कपड़ा मिलें घाटे में चल रही थीं, इसलिए मिल मालिक इस मुद्दे पर बातचीत को राजी नहीं हुए। मामला तत्कालीन श्रमायुक्त के पास पहुंचा। श्रमायुक्त ने मजदूरों और मिल मालिकों के बीच समझौता कराया कि वेतनमान के नवीनीकरण के लिए आयोग गठित किया जायेगा, जो दोनों पक्षों की स्थिति को जान-समझकर अपनी रपट देगा।

इस समझौते के आधार पर दिसम्बर, १९८५ में केके पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। २४ दिसम्बर, १९८८ को आयोग ने जो रपट दी, उसमें ६० रुपए मासिक अंतरिम राहत के साथ मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने, मजदूरों की संख्या कम करने और मशीनें बढ़ाने की बात कही गयी। काम के घंटे बढ़ाने के समर्थन में बंबई की कपड़ा मिलों का हवाला दिया गया, जहां मजदूर अधिक काम करते हैं। इन सिफारिशों से मजदूर भड़के, पर मालिकों ने आयोग की सिफारिशें लागू करने में गजब की फुर्ती दिखायी।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ६ के अनुसार कोई अवार्ड पहले उप्र शासन को दिया जाता है और इसके ३० दिन बाद शासन इसे प्रकाशित करता है। पर शासन ने यह अधिकार पहले ही पाण्डेय आयोग को दे दिया था। इसलिए अवार्ड २४ दिसंबर, १९८८ को प्रकाशित कर दिया गया। कानूनी तौर पर कोई अवार्ड प्रकाशन के ३० दिन बाद ही लागू होता है। इसलिए मिल मालिकों ने २० जनवरी को नोटिस चस्पा कर दिया। २४ जनवरी को अवार्ड लागू हुआ और मजदूरों ने इसका विरोध शुरू किया। उन्होंने बढ़ाये गये घंटों में काम करना बंद कर दिया। जवाब में मिल मालिकों ने श्रमिकों के पैसे काटना शुरू कर दिया। मजदूरों ने मिल फाटक पर नारेबाजी और विरोध सभाएं शुरू कर दीं। १९ फरवरी को मजदूरों ने श्रमायुक्त को नोटिस देकर अवार्ड वापस लेने का अनुरोध किया। श्रमायुक्त ने औद्योगिक न्यायाधिकरण को पत्र लिख कर इस पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। इसके विरोध में मिल मालिकों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। मजदूरों ने भी पाण्डेय अवार्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। २२ फरवरी से मजदूरों ने कानपुर के जुही रेलवे पुल के निकट रेल जाम आंदोलन की शुरुआत कर दी।

राज्य सरकार ने मजदूर नेताओं के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वह पाण्डेय अवार्ड वापस लेने को तैयार है, शर्त यह कि आंदोलन तत्काल समाप्त कर दिया जाये। मजदूर इसके लिए राजी न हुए। मामला विधानसभा में उठा। राज्य सरकार ने विधायक रामनारायण पाठक की अध्यक्षता में पांच विधायकों की एक समिति गठित करके आंदोलन खतम कराने का दायित्व उसे सौंपा। रामनारायण पाठक समिति ने मिल मालिकों और मजदूरों से लम्बी बात की, पर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अन्त में रामनारायण पाठक समिति ने पाण्डेय अवार्ड को वापस लेने की सिफारिश की। २७ फरवरी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इस व्यवस्था के साथ पाण्डेय अवार्ड वापस लेने की घोषणा की कि मजदूरों को मिलनेवाली ६० रुपए मासिक की अंतरिम राहत जारी रहेगी। श्रमिकों ने सरकारी फैसले का स्वागत करके २७ फरवरी को रेल जाम आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके पूर्व देश में कभी भी इतना बड़ा और सफल रेल चक्का जाम आंदोलन नहीं हुआ था। इस आंदोलन से पांच दिनों में सरकार और मिल मालिकों को करीब पांच करोड़ रुपए की क्षति उठानी पड़ी।

—रामपाल सिंह

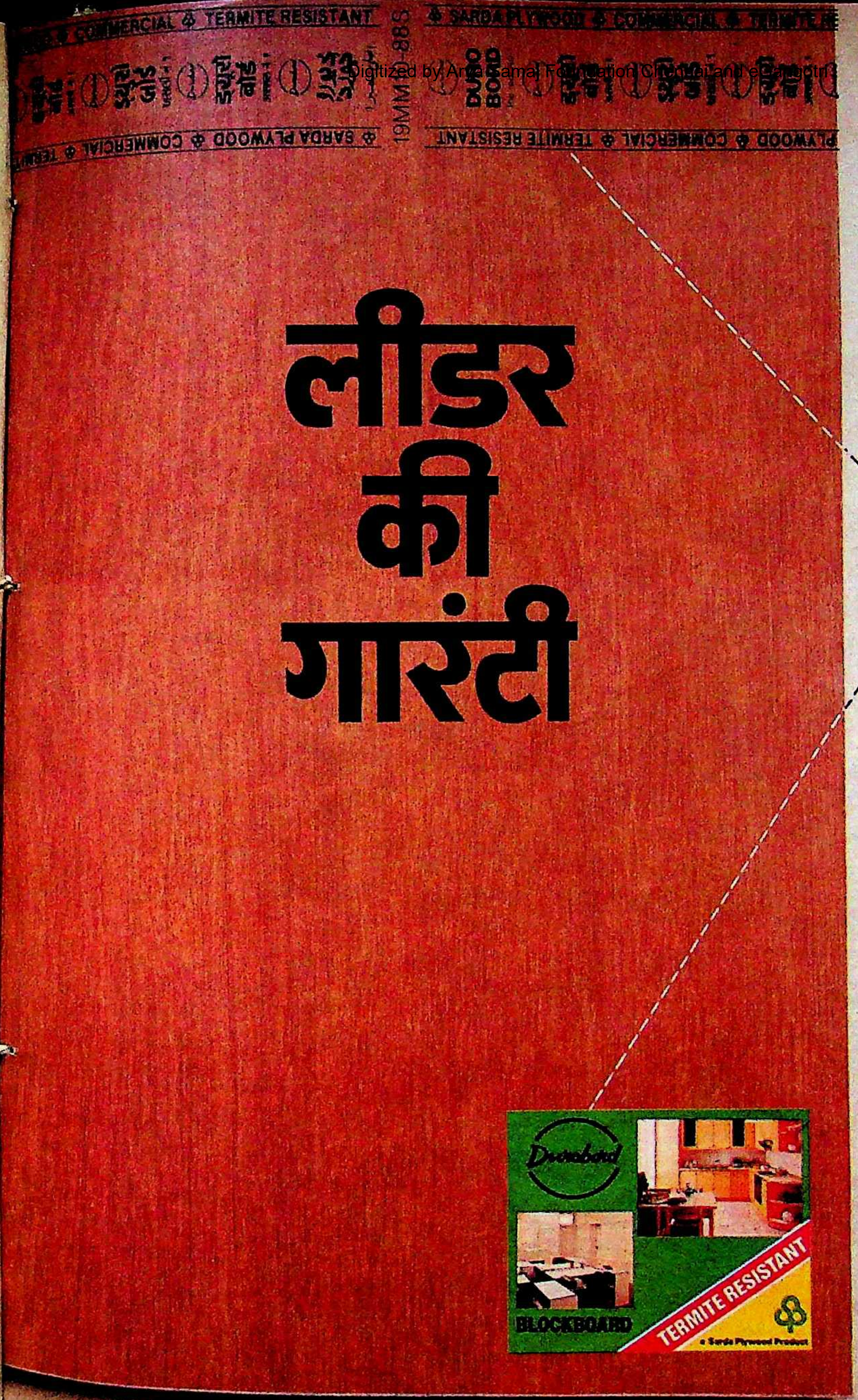
COMMERCIAL ❀ TERMITE RESISTANT
❀ SARDA PLYWOOD ❀ COMMERCIAL ❀ TERMITE RE
19MM 885
DURO BOARD
Durobord
BLOCKBOARD
TERMITE RESISTANT
a Sarda Plywood Product

लीडर की गारंटी

नकल से दुहरी सुरक्षा

हरचंद कोशिशों के बावजूद हम ड्यूरोबोर्ड की नकल एकदम रोकने में सफल नहीं हुए हैं । इसलिए हमने प्रत्येक ड्यूरोबोर्ड पर आपके जाने-पहचाने लेबल के साथ एक स्ट्रिप भी लगा दी है । ध्यान दीजिये कि आप जो ड्यूरोबोर्ड खरीद रहे हैं उस पर वे दोनों है ।

Durobord™

असली नं - १

ड्यूरो-
ब्लॉकबोर्ड का हीरो

**सारदा प्लाइवुड
इन्डस्ट्रीज लिमिटेड**
वर्क्स: जेपुर (आसाम)
जनरल सेल्स ऑफिस:
१/[illegible]धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली ११० ०५५

DPS. SPI. 882 HIN

क्षेत्रवाद के सहारे सत्ता के सपने : एबीएसयू प्रदर्शनकारी दुधनोई में

छाया : विकास चक्रवर्ती

बोडोलैंड आंदोलन

क्षेत्रीयतावाद का एक और नासूर

असम की कबीलाई बोडो जाति ने बोडोलैंड के लिए २१ वर्ष पहले जो आंदोलन छेड़ा था, उसने अब हिंसक रूप धारण कर लिया है। लूटपाट, हिंसा और आगजनी की वारदात से निबट सकने में असमर्थ हो रही महंत सरकार ने केंद्र पर बोडोलैंड आंदोलन को हवा देने का आरोप लगाया है। क्या सचमुच केंद्र सरकार महंत सरकार को कमजोर करने के लिए बोडोलैंड आंदोलन को राजनीतिक हथियार बना रही है?

उन्मादी माहौल : पब्लिक मीटिंग का दृश्य

छाया : विकास चक्रवर्ती

बोडोलैंड आंदोलन के एकबारगी हिंसक हो उठने से असम के युवा मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत बुरी तरह सांसत में हैं। उल्लेखनीय है कि वे अपने शासन के चौथे वर्ष में हैं इसलिए यदि आंदोलनों की रफ्तार थमी नहीं, तो आगामी चुनाव उनके लिए भारी तबाही का होगा।

"बोडोलैंड की मांग को अगर सचमुच गंभीरता से निबटाने की कोशिश पहले की गयी होती, तो आज स्थिति इतनी अनियंत्रित नहीं होती। गैर कांग्रेस शासित प्रांतों में इस तरह के मामलों के सिर उठाने की प्रतीक्षा तो केंद्र करता ही रहता है, ताकि फौरन उसे हस्तक्षेप करने का मौका मिले।" उद्विग्न होकर 'माया' से यह टिप्पणी करते हैं प्रफुल्ल महंत की सरकार में काबीना मंत्री रह चुके प्रो० थानेश्वर बोरो। थानेश्वर बोरो इसी आदिवासी जाति के हैं। वाकई जनवरी के अंतिम दिनों से ही बोडो आंदोलनकारियों ने जिस तरह का आक्रामक तेवर अख्तियार किया है उसने असम गण परिषद की सरकार को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। साथ ही, भविष्य के लिए भी इस बात का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि चिकनी-चुपड़ी बातों से वे रास्ते पर नहीं आनेवाले। अगर बोडोलैंड की मांग पूरी नहीं की गयी, तो बोडो आंदोलनकारी अपना हिंसक संघर्ष जारी रखेंगे। १९८८ के नवंबर माह से बोडो आंदोलनकारी इस उम्मीद के तहत खामोश थे कि शायद उनकी मांग के सिलसिले में असम-सरकार कोई सार्थक पहल करेगी। पर जब उस दिशा में कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, तो फिर बोडो आंदोलनकारी जनवरी के अंतिम सप्ताह से उग्र होने लगे। 'आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन' के अध्यक्ष उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा और 'यूनाइटेड ट्रायबल नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट' के अध्यक्ष बिनय बासुमत्री ने ऐलान कर दिया कि असम के आदिवासियों ने पहले भी बहुत गोलियां खाकर जानें गंवाई हैं और इससे भी अधिक जानें गंवाने के लिए वे लोग तैयार हैं। असम की सरकार यदि चाहे, तो पूरे प्रदेश के आदिवासियों को गोलियों से भून दे और आदिवासियों की हत्या करनेवाली सरकार के रूप में गौरवान्वित हो।

चिंताजनक मोड़ : बोडोलैंड की मांग लेकर संघर्षरत आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और युनाइटेड नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट ने १६ फरवरी से १२० घंटे के असम बंद का आह्वान किया, तो मुख्यमंत्री महंत और ज्यादा आशंकित हो उठे। दिल्ली में उन्होंने गृहमंत्री बूटा सिंह से भी आंदोलन की संभावनाओं पर व्यापक परामर्श किया तो बूटा सिंह ने उन्हें मशविरा दिया कि वे गुवाहाटी लौटकर तत्काल बोडो आंदोलनकारियों से बातचीत कर स्थिति सहज करने की चेष्टा करें। ऊपरी तौर पर महंत को राहत देने के लिए बूटा सिंह ने दिल्ली से यह बयान भी जारी कर दिया था कि अलग बोडोलैंड की मांग अव्यावहारिक है और असम का बंटवारा संभव नहीं है। इसी बीच असम के गृहमंत्री भृगु कुमार फूकन ने भी बयान दिया था कि उनकी सरकार अभी तक बोडो आंदोलनकारियों से नरमी से पेश आती रही है, पर अब इन आंदोलनकारियों को सख्ती से ठिकाने लगाया जायेगा। पर इन तमाम चेतावनियों ने बजाय बोडो आंदोलनकारियों को आंदोलन के रास्ते से वापस लौटाने के और भड़का दिया। लिहाजा ११ फरवरी से बोडो आंदोलनकारी खुलकर हिंसा पर उतारू हो गये। ११ फरवरी को असम के कोकराझाड़ जिले, जो बोडो आंदोलनकारियों का मुख्यालय है, के निकट एक प्राइवेट बस में शक्तिशाली बम के विस्फोट से १२

सख्ती से निबटेंगे: गृहमंत्री फूकन

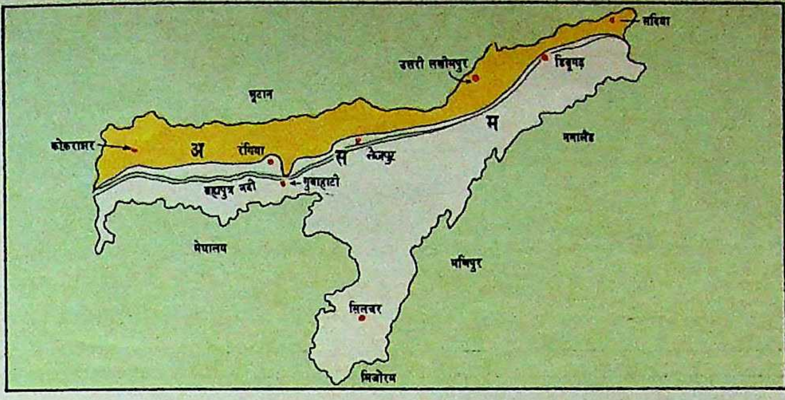

ठीक से नहीं निबटा गया: बोरो

लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बासुगांव से बोंगाईगांव जा रही इस बस में बम का इतना जबर्दस्त विस्फोट हुआ कि हादसे में मृत कई लोगों के शरीर के विभिन्न अंग लगभग सौ मीटर दूर मिले। इस हादसे के तुरंत बाद बोंगाईगांव विधानसभा क्षेत्र से असम गण परिषद के विधायक फणिभूषण चौधरी को मुख्यमंत्री महंत ने असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर भेजा और इस कांड से जुड़े आंदोलनकारियों को तत्काल पकडने की हिदायत असम के पुलिस महानिदेशक को दी। फरवरी के पहले सप्ताह से ही बोडो आंदोलन के गुरिल्लों ने छिटपुट कहर मचाना शुरू कर रखा था। कोकराझाड जिले में ही भूटान की सीमा पर स्थित एक पुलिस पिकेट के पास बोडो आंदोलनकारियों ने पुलिस के जवानों से सात राईफलें और सारे कारतूस छीन लिए, तो असम की राजधानी दीसपुर में बैठे गृहमंत्री भृगु कुमार फूकन ने परेशान होकर तत्काल मुख्य सचिव, गृह आयुक्त व पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलायी और फरमान जारी किया कि पूरे कोकराझाड़ जिले को पुलिस छान डाले तथा जहां भी उग्रवादी मिलें उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाये। लिहाजा, एकतरफ जहां असम पुलिस कोकराझाड़ जिले के गांव-गांव में गिरफ्तारी के आपरेशन में जुट गयी, वहीं बोडो आंदोलनकारी भी अपनी इस मुहिम में जुट गये कि चाहे जितना खून-खराबा हो, वे भी इस बार सरकार को हिला कर रख देंगे।

इस तरह पुलिस और बोडो आंदोलनकारियों में हिंसक टकराव शुरू हो गये। असम सरकार ने आखिरकार इन हिंसक वारदातों के निबटारे के लिए मारने व संभालने की नीति अपनायी। मसलन, एकतरफ जहां बोडो आंदोलनकारियों की धर-पकड़ करने के लिए पुलिस की लगाम कस दी गयी, वहीं गृहमंत्री भृगु फूकन ने आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा को वार्ता के लिए २८ फरवरी को आमंत्रित किया। पर इस सबसे बात बनी नहीं। १३ फरवरी को बोडो आंदोलनकारियों ने कोकराझाड़ जिले के सेसपानी स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर तारिणी कांत कालिता का खून कर ट्रेन के चालक को गोली मारकर आहत किया। साथ ही चार रेल कर्मचारियों को अपहृत भी कर लिया। ११ फरवरी से १४ फरवरी तक बोडो आंदोलनकारियों ने न सिर्फ पंद्रह-बीस से अधिक लोगों के प्राण लिए, बल्कि अनगिनत पुल, सवारियों तथा घरों को जलाकर राख कर दिया था। नतीजतन, विवश होकर सरकार को कोकराझाड़ के इलाके में सेना को चौकन्ना करना पड़ा। १६ फरवरी से शुरू बंद का कार्यक्रम भी कम हिंसक नहीं गुजरा। १७ फरवरी को असम गण परिषद की रूनीखाटा इकाई के अध्यक्ष विनोद दत्त की गोली मारकर जान ले ली गयी। इतना ही नहीं, स्थिति तब और संगीन हो गयी जब नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस तथा कामरूप एक्सप्रेस पर भी आंदोलनकारियों ने फायरिंग की तथा बचाव के लिए रेलवे पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। इस तरह स्थिति बेकाबू होती चली गयी। विनोद दत्त की हत्या के बाद जब १८ फरवरी को कोकराझाड़ जिले के आरक्षी अधीक्षक तथा आयुक्त विनोद के घर मामले की तहकीकात के लिए जा रहे थे, तो बम से उन लोगों पर भी हमला किया गया। इत्तफाक से दोनों जान गंवाने से बच गये। असम के पुलिस महानिदेशक सुब्रह्मण्यम भी बेचैन थे कि स्थिति पर नियंत्रण कैसे किया जाये। दारांग जिले के चार पुल जब आंदोलनकारियों ने जला डाले, तो पुलिस पहुंची। आंदोलनकारी पुलिस पर टूट पड़े। कोरियापाडा में इसी तरह एक हजार से अधिक लोगों ने पुलिस को अपने घेरे में लेकर फायरिंग शुरू की। नतीजतन, जवाबी फायरिंग करके बड़ी मुश्किल से पुलिस वहां से निकल सकी। आंदोलनकारियों से निबटना पुलिस के लिए बेहद भारी पड़ रहा था, क्योंकि सबके सब मरने-मारने को उतारू थे। आंदोलनकारियों ने 'प्लेन ट्रायबल काउंसिल आफ असम' के एक प्रमुख कार्यकर्ता बीरेन नरजरी को भी जिगिरबिल इलाके में मौत के घाट उतार दिया। १८ फरवरी को मुख्यमंत्री महंत ने आंदोलनकारियों से अपील की कि वे उन सब से सहानुभूति पूर्वक बात करने को तैयार हैं, इसलिए वे लोग हिंसक गतिविधियां बंद कर दें। गृहमंत्री भृगु फूकन ने आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा, जो १८ फरवरी को कूच बिहार में थे, के पास वार्ता

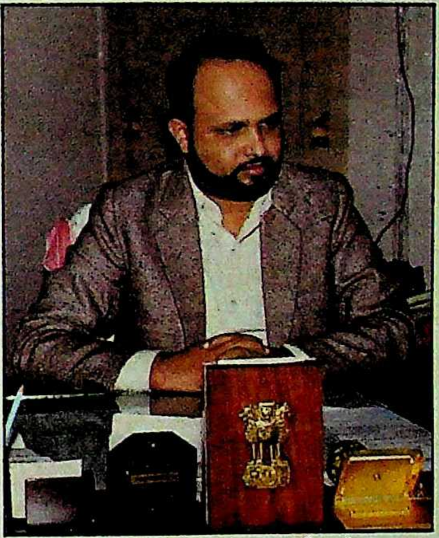

तबाहियों की चिंता: मुख्यमंत्री महंत

बहरहाल, हिंसक बोडो आंदोलन, आटोनामस स्टेट डिमांड कमेटी का आंदोलन, अपनी पार्टी के विक्षुब्धों की भितरघाती मुहिम और मिजोरम व नगालैंड चुनाव की विजय से अतिउल्लसित कांग्रेस से मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत पिछले दिनों की भांति निबट सकेंगे या इन संकटों से जूझना उनके लिए भारी पड़ेगा इस संबंध में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्टैला

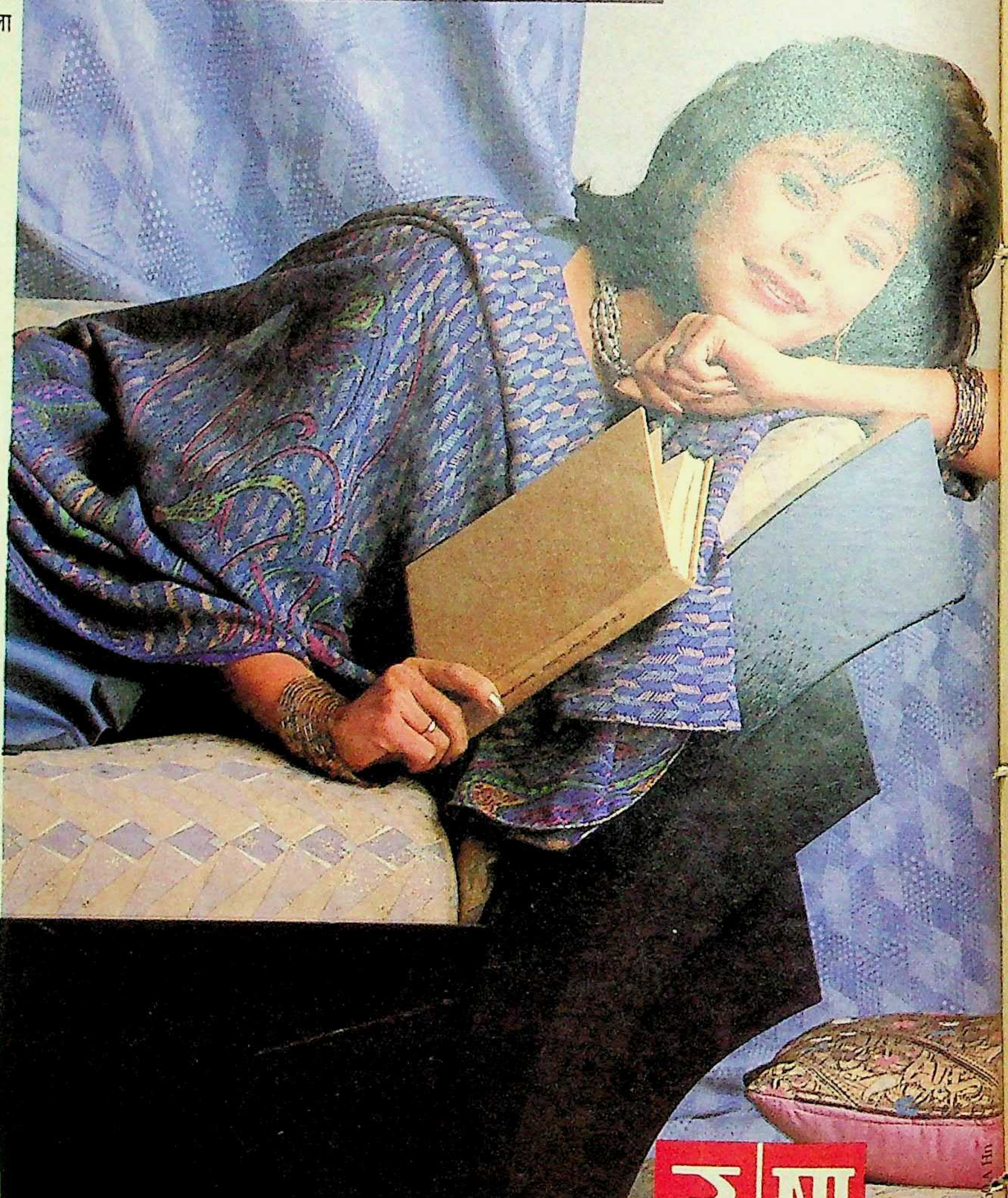

उषा का अंदाज़!

सुंदर रूप-रंग, दिलकश अंदाज़।
मोतियों-सा सफ़ेद और
दमकता हुआ भूरा।
डबल बॉल बेयरिंग-युक्त।
उषा की 40 वर्षों से अधिक की
उत्कृष्ट तकनीक से रचा।

आपका अंदाज़!

आज 2.73 करोड़ से भी अधिक
उषा पंखों के संतुष्ट ख़रीदार
भारत में और विश्व के
60 देशों में फैले हैं।
उषा पंखें—सीलिंग, टेबल, पेडेस्टल,
वॉल, कैबिन और एग्ज़ॉस्ट पंखों
की विस्तृत रेंज में।
इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
को भरोसा है उषा पर।

उषा

भारत का सर्वाधिक बिकने वाला पंखा

Contract JEW 2076 A Hn.

का निमंत्रण लेकर अपना दूत भी भेजा। पर ब्रह्मा ने इस बार भी इस निमंत्रण को तरजीह नहीं दी। इस बीच समाज कल्याण मंत्री रेखारानी दास बोरो ने भी आंदोलनकारियों से बातचीत की और प्रस्ताव दिया कि बोडो बहुल क्षेत्र में छठे शिड्यूल के तहत वे अधिकाधिक अधिकार ले लें। पर रेखारानी की वार्ता भी विफल साबित हुई। १९ फरवरी को आंदोलनकारियों ने सरकार को 'अल्टीमेटम' दे दिया कि यदि 'बोडो वालंटियर फोर्स' के संयोजक सोनाराम बागलारी को बगैर शर्त नहीं छोडा गया, तो वे लोग और भी भीषण हिंसक कार्रवाई करेंगे।

उग्र होता आंदोलन: इस बीच पुलिस से मुठभेड़ों में कई आंदोलनकारी मारे जा चुके थे। २० फरवरी को आंदोलनकारियों ने फिर धमकी दी कि अगर ४८ घंटों के अंदर दारांग व कोकराझाड़ जिले से सेना तथा अर्द्धसैनिक बल को नहीं वापस लिया गया, तो वे लोग पूरे प्रदेश में हथियारबंद संघर्ष छेड़ेंगे। २१ फरवरी को जब आंदोलनकारियों के १२० घंटे के बंद की मियाद पूरी हुई, तब तक बेहिसाब खून-खराबा हो चुका था। असम गण परिषद के प्रमुख नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि असम में अराजकता कायम करने की रणनीति केंद्र सरकार की है तथा स्वयं गृहमंत्री बूटा सिंह तथा गृह राज्यमंत्री संतोष मोहन देव बोडो आंदोलन को पीछे से सहयोग दे रहे हैं। असम गण परिषद के लोकसभा सदस्य दिनेश गोस्वामी ने भी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रहे धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बूटा सिंह तथा संतोष मोहन देव पर बोडो आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया। संतोष मोहन देव ने तो तत्काल इसका खंडन किया, पर असम गण परिषद् के कई नेताओं ने फिर बढ़-चढ़ कर अगले दिन आरोप लगाया कि चंद गिरफ्तार बोडो आंदोलनकारियों ने स्वीकार किया है कि बूटा व देव की शह पर वे सब सक्रिय थे। २४ फरवरी को दीसपुर में महंत ने अपनी काबीना की बैठक में पूरी स्थिति की नये सिरे से समीक्षा की। मुख्यमंत्री महंत ने यह संभावना भी व्यक्त की कि भूटान के इलाके में बोडो उग्रवादियों को प्रशिक्षण मिल रहा है अतः केंद्र को भूटान की रायल-सरकार को इस बात की ताकीद करनी चाहिए। असम के पुलिसे महानिदेशक ने यह आशंका व्यक्त की कि 'गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट' वालों से भी बोडो आंदोलनकारियों को हथियार की मदद मिल रही है क्योंकि उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा ने इस सिलसिले में दार्जिलिंग की यात्राएं भी की थीं। बहरहाल, असम सरकार द्वारा २८ फरवरी की वार्ता के लिए भेजे गये निमंत्रण को बोडो आंदोलनकारियों ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जब तक असम सरकार अपनी नीयत ठीक नहीं करेगी कोई भी वार्ता संभव नहीं हो सकती। आंदोलनकारियों ने गिरफ्तार बोडो आंदोलनकारियों को छोड़ने की मांग की तथा कहा कि १९८७ का आतंकवादी निवारक कानून रद्द किया जाये।

बोडोलैंड लेकर रहेंगे : ब्रह्मा

कांग्रेस की चाल: किंतु सवाल यह है कि आखिर एकबारगी बोडो आंदोलनकारी इस हद तक क्यों उग्र हो उठे? असम गण परिषद के नेताओं का तर्क है कि मिजोरम व नगालैंड में सत्ता हासिल करने के पश्चात अब उत्तर-पूर्वी प्रांतों में एकमात्र असम ही ऐसा प्रांत रह गया है जो कांग्रेस की मुट्ठी से बाहर है। इसलिए मिजोरम व नगालैंड की जीत से उत्साहित कांग्रेस नेतृत्व अब हर सूरत में असम को अपनी जद में लेने के लिए बेचैन है। लिहाजा, पश्चिम बंगाल में विधानसभाई चुनाव के पूर्व जिस तरह गोरखालैंड आंदोलन को केंद्र ने हवा दी, उसी तर्ज पर असम में भी विधानसभाई चुनाव के पूर्व कांग्रेस सुनियोजित रणनीति के तहत बोडो आंदोलन में पेट्राल डाल रही है। असम गण परिषद के नेता मिसाल पेश करते हुए कहते हैं कि जब कभी भी कांग्रेस असम की हुकूमत से उखड़ी तभी 'उदयाचल' या 'बोडोलैंड' सरीखे आंदोलनों ने असम में हाथ-पांव फैलाये। शुरुआती दौर में महंत की सरकार ने असम समझौते की धारा दस को कारगर करने की मुनादी इस उम्मीद से की कि बोडो इससे प्रसन्न हो उठेंगे। किंतु बाद में वायदा पूरा नहीं हुआ तभी बोडो आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी।

अलग बोडोलैंड की मांग की पृष्ठभूमि लगभग २१ वर्ष पुरानी है। १५ फरवरी १९६७ को इसी मांग को लेकर संघर्ष करने के इरादे से 'आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन' बनायी गयी थी। उसी दौर में २७ फरवरी १९६७ को आदिवासी संगठन 'प्लेंस ट्रायबल काउंसिल आफ असम, (पीटीसीए) की भी नींव डाली गयी थी। पर इन दोनों संगठनों में बाद में दरार पड़ गयी, क्योंकि पीटीसीए ने बाद में बोडोलैंड की मांग के सवाल पर एतराज कर दिया और उसके नेता जनता पार्टी से मिलकर सांसद और विधायक बनने के चक्कर में मशगूल हो गये। नतीजतन, बोडोलैंड के सवाल पर आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन अकेली पड़ गयी। पर वर्षों बाद १९ अप्रैल १९८४ को 'यूनाइटेड ट्रायबल नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट' की स्थापना ने बोडो आंदोलन को बल दिया, क्योंकि आल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के साथ बोडो आंदोलन में यह फ्रंट भी कंधे से कंधा मिलाकर ४० लाख बोडो आदिवासियों के सवाल पर संघर्षरत हो गया। असम के वर्तमान क्षेत्रफल ७८,५२३ वर्ग किलोमीटर में से २५,४७८.१ वर्ग किलोमीटर बोडो आंदोलनकारी बोडोलैंड की खातिर मांग रहे हैं।

अपनों की साजिश: बवंडरों में फंसे रहना ही प्रफुल्ल महंत की नियति है। जब वे एक तूफान से निकलते हैं, तो अगला तूफान उनके लिए प्रतीक्षारत होता है। कांग्रेस जहां एकबार फिर असम में कमर कसने के लिए तोड-जोड़ कर रही है, वहीं असम गण परिषद में महंत से विक्षुब्ध विधायकों व पूर्व मंत्रियों की जमात भी पूरी तरह शांत नहीं बैठी है। अपनी पार्टी के विक्षुब्धों को विगत २ फरवरी को असम गण परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में महंत ने तत्क्षण खामोश तो कर दिया, पर सच यह है कि अधिकांश विक्षुब्ध अभी भी महंत के खिलाफ पलीता बिछाने की मनोदशा से मुक्त नहीं हुए हैं। २ फरवरी को आयोजित पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के बारे में प्रफुल्ल महंत को पहले से शक था कि उनके विरुद्ध कुछ लोग शोर-शराबा करेंगे। इसलिए महंत अपनी पार्टी की ४५ जिला समितियों में से ३७ जिला समितियों के अध्यक्ष का लिखित समर्थन उस बैठक में अपने साथ लेकर पहुंचे थे कि पार्टी के हित में महंत जिसे चाहें निकाल बाहर कर सकते हैं। महंत के इस दांव से पार्टी के विक्षुब्ध तत्काल मात खा गये। पर महंत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उनके खिलाफ विक्षुब्धों का अभियान थमा अवश्य है, पर खतम नहीं हुआ है। महंत के सामने सिर्फ उग्र बोडोलैंड आंदोलन ही एक समस्या नहीं है। कर्बी स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा संचालित 'आटोनामस स्टेट डिमांड कमेटी, (एएसडीसी) भी असम गण परिषद के लिए परेशानी बनकर उभर रही है। यह संगठन असम के पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए 'आटोनामस' व्यवस्था की मांग कर रहा है। हाल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में एएसडीसी ने असम गण परिषद् को भारी शिकस्त भी दी है। २५ जनवरी '८९ को एएसडीसी वाले जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर काबिज हो गये, तो असम गण परिषद ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भंग करने के लिए असम के राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह को प्रतिवेदन भी दिया।

बहरहाल, हिंसक बोडो आंदोलन, आटोनामस स्टेट डिमांड कमेटी का आंदोलन, अपनी पार्टी के विक्षुब्धों की भितरघाती मुहिम और मिजोरम व नगालैंड चुनाव की विजय से अतिउल्लसित कांग्रेस से मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत पिछले दिनों की भांति निबट सकेंगे या इन संकटों से जूझना उनके लिए भारी पड़ेगा इस संबंध में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हां, इतना जरूर है कि इन आंदोलनों, विशेषकर बोडोलैंड आंदोलन ने प्रफुल्ल महंत को सांसत में अवश्य डाल दिया है।

छाया: दीपक कुमार

—विकास कुमार झा

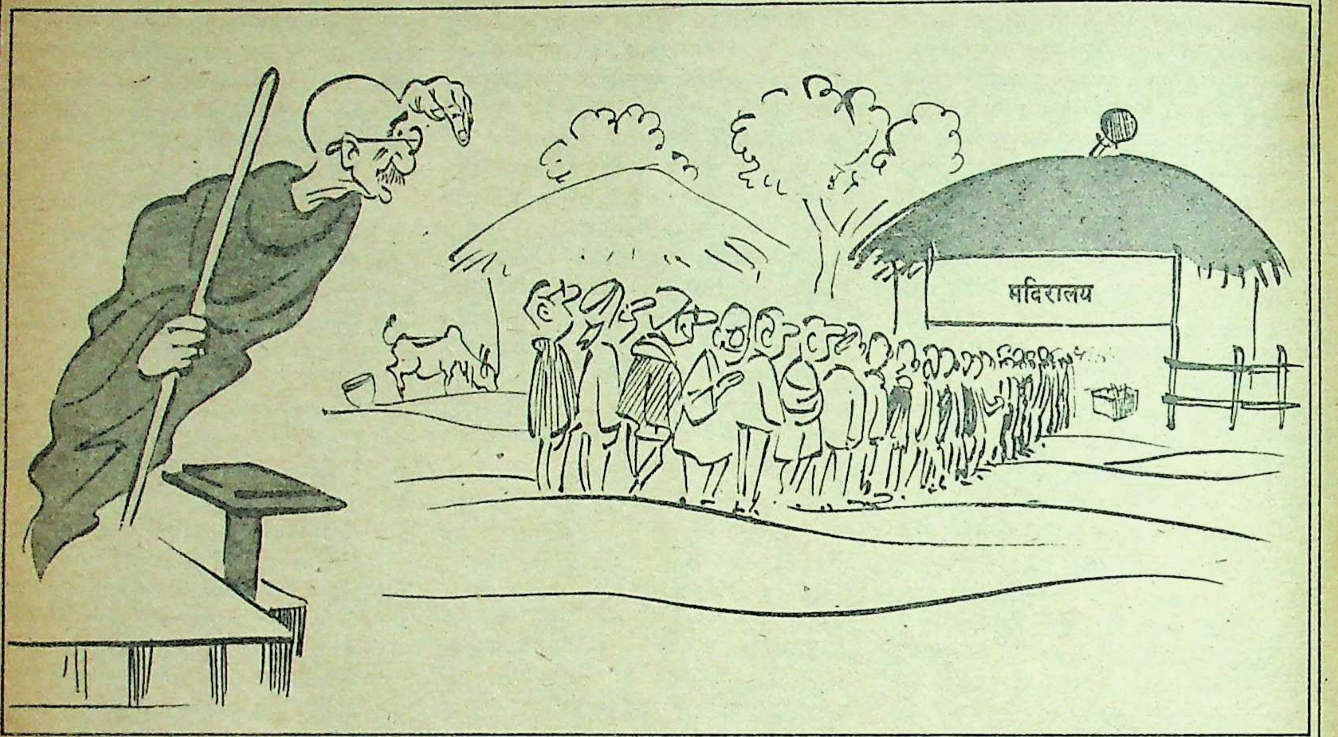

गांधी का गुजरात : अवैध शराब के जहरीले शिकंजे में

यों तो गुजरात महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और इस पर तुर्रा यह है कि यह देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां मद्यनिषेध लागू है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि इस समय गुजरात में अवैध शराब का धंधा कुटीर उद्योग की तरह राजनेताओं और पुलिस की छत्रछाया में निर्बंध फलफूल रहा है। इसी अवैध धंधे के जहर ने ५-६ मार्च को बड़ौदा में सैकड़ों लोगों की जान ली है। लेकिन इस धंधे ने गुजरात को जिस शिकंजे में कस रखा है, उसको देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि आगे ऐसी त्रासदियां नहीं होंगी ?

अहिंसा और मद्य-मुक्ति के मसीहा महात्मा गांधी का गुजरात अब कहीं से नहीं लगता कि सदी के सबसे आदर्श महापुरुष ने यहीं जन्म लिया और इसी की माटी में जीवन के आदर्श पाये थे। गुजरात में पिछले एक दशक में अवैध शराब का करोड़ों रुपए का धंधा ऐसा पनपा कि यदि आज गुजरात को शराब विक्रेताओं का जन्नत कहा जाये, तो गलत न होगा। अवैध शराब के धंधे ने इस राज्य में ऐसी जड़ जमा ली है कि शराबबंदी का कानून क्या, यदि कानून लागू करवानेवाली मशीनरी भी बदल दी जाये, तो उसको उखाड़ फेंकना आसान नहीं। आज स्थिति यह है कि छोटे-से-छोटे गांव से लेकर छोटे-बड़े शहरों तक में शराब बनाने का काम खुलेआम हो रहा है और किसी को किसी समय भी उसकी पसंदीदा शराब सस्ते दाम में उपलब्ध हो सकती है।

इस धंधे का सबसे घातक परिणाम यह हुआ कि राज्य के पुलिसजन व्यवसायियों में तब्दील हो गये और शराब विक्रेता राजनीतिक आका बन बैठे। शराब विक्रेताओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता और राजनीति में बेजा दखलंदाजी का नतीजा यह हुआ कि हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच टकराहटें शुरू हो गयीं और देखते ही देखते सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मिसाल रह चुका राज्य सांप्रदायिकता की रणभूमि बन गया। सद्भाव के लिए विख्यात बड़ौदा आये दिन दंगाग्रस्त तो रहता ही है, साथ ही ५-६ मार्च को देश के भीषणतम विषैली शराब कांडों की सूची में भी उसका नाम आ गया। इस कांड में १५० लोगों ने जान गंवायी है और अनेक अंधे हुए हैं।

गुजरात की राजधानी और देश का टेक्सटाइल केंद्र रह चुका प्रमुख शहर अहमदाबाद अब महज एक व्यापारिक स्थल रह गया है। इसकी वजह भी आये दिन होनेवाले दंगे ही हैं। यह शहर शराब विक्रेताओं, पुलिस और राजनीतिज्ञों की मिलीभगत से संत्रस्त है। मार्च १९८५ में जब अहमदाबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए, तो सर्वाधिक प्रभावित इलाके कालूपुर के कांग्रेस-इ के नेता एमएच बारेजिया को गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि उन पर उपद्रव फैलाने के खुले आरोप थे। जब बारेजिया को तीन महीने बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, तो शहर में छुरेबाजी की एक दिन की औसत १५ वारदातें कम होकर २ पर पहुंच गयीं। बारेजिया फौजदारी मामलों के वकील भी हैं और कहा जाता है कि उनके कुख्यात अपराधी सरगनाओं आलमजेब और लतीफ से करीबी संबंध हैं।

कानून का इस तरह उल्लंघन मात्र बड़ौदा और अहमदाबाद में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और

गावों में भी किया जा रहा है। एक बार तो स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी कि गुजरात केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बन गया था। किसी कारगर विकल्प के अभाव में केंद्र को भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ, ईमानदार अधिकारी एमएम सिंह को गुजरात पुलिस का सर्वेसर्वा बनाने पर मजबूर होना पड़ा था।

सर्व सुलभ शराब: गुजरात में शराब की उपलब्धता पर बातचीत करते हुए एक शराब प्रेमी ने स्मरण करते हुए कहा, "देशी शराब की एक बोतल हासिल करना पुराने दिनों में कभी समस्या नहीं थी। हां, व्हिस्की या रम की बोतल के साथ शाम बिताने का कई दिनों पहले कार्यक्रम बनाना पड़ता था। कितु अब तो विदेशी शराब के लिए भी मारे-मारे फिरने की जरूरत नहीं। जेब में पैसे होने चाहिए छोटे-से-छोटे गांव में रम और व्हिस्की मिल जायेगी।" अनुमान है कि राज्य में सालाना ६०० से ९०० करोड़ रुपए के बीच शराब का कारोबार होता है। यह रकम राज्य के मौजूदा बजट घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

एक पर्यवेक्षक का मानना है कि राज्य में शराबबंदी हर किस्म की शराब की कीमतों को बढ़ाने के लिए गारंटी बन गयी है। १९८० की जनगणना के अनुसार गुजरात की आबादी ३.४० करोड़ है। इस विशाल आबादी को देखते हुए विभिन्न प्रकार की शराबों की सहज उपलब्धता यदि उपर्युक्त सालाना बिक्री के आंकड़ों को पार कर जाये, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

'माया' ने राज्य के शहरी व ग्रामीण इलाकों के अपने एक महीने के दौरे में पाया कि अहमदाबाद व सूरत शहर शराब से पटे हुए हैं। बड़ौदा इनसे कुछ पीछे है। इसी तरह राज्य के चौथे प्रमुख शहर राजकोट में अवश्य शराब की बोतल हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। इसका यह मतलब नहीं कि कोई ऐसी खास जगह है जहां शराब का धंधा केंद्रित है। स्थिति तो यह है कि शहर-तो-शहर, ग्रामीण इलाके, यहां तक कि सौराष्ट्र भी शराब के मामले में पीछे नहीं है। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां शराब बनाने का धंधा न होता हो। गुजरात के दूरदराज ग्रामीण इलाकों और संपन्न शहरी इलाकों की यात्रा से शराब के बारे में यह तथ्य उजागर हुआ कि शराब चाहे स्थानीय हो या तस्करी की, अधिकांशतः मिलावटी होती है। पोरबंदर, वेरावाल व कांडला जैसे सागरतटीय नगरों के अलावा दक्षिणी गुजरात में धनी लोगों के लिए विदेशों से लायी गयी उम्दा स्काच भी उपलब्ध रहती है।

महात्मा गांधी का दुख: महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर ने तो एक नायाब सूझबूझवाले शराब विक्रेता को जन्म दिया है। उसने जमीन के नीचे एक टैंक बनवाकर उसमें ५० हजार लीटर शराब भर दी है और उसे एक हैंडपंप से जोड़ रखा है। उसके अड्डे पर चौबीसों घंटे बेहतर ग्राहक-सेवा की परंपरा का पालन करते हुए हैंडपंप चलाकर खरीदारों को शराब दी जाती है। यह अलग बात है कि दिल्ली में चिरनिद्रा में लीन महात्मा गांधी की आत्मा को यह जानकर दुख होता होगा कि उनके जन्मस्थान के ऐन करीब शराब ४ रुपए फी गिलास खुलेआम बिकती है। कुछ वर्षों पूर्व एक सजग जिला पुलिस अधीक्षक ने जब शराब के धंधेबाजों पर हमला बोला था, तो राज्य के राजनीतिक नेता उसके खून के प्यासे हो गये थे, क्योंकि किसी न किसी रूप में वे भी शराब के धंधे से जुड़े थे। पुलिस अधिकारी ने जब कड़ा रुख अपनाया, तो शराब का बनना कम हुआ, किंतु उसी समय जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गयी। फिर क्या था? नेता तो बहाने की ही तलाश में थे। मौका पाते ही भूखे जानवरों की तरह टूट पड़े।

कुछ समय पहले राजकोट के जिलाधीश कार्यालय परिसर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। जूनागढ़ के वनस्थली इलाके का एक शराब विक्रेता उम्दा क्वालिटी का कायल था। उसके प्रशिक्षित कुत्ते हर नयी खेप की; बाजार में आपूर्ति के पहले, स्वयं चखकर जांच करते थे। इत्तफाक से एक खेप जहरीली थी। नतीजतन कुत्तों सहित शराब विक्रेता का सर्वनाश हो गया। इसी प्रकार गुजरात का छारंगर का इलाका है, जहां शराब बनाना घरेलू उद्योग माना जाता है। वहां से उठती तेज गंध का अहसास एक मील दूर से ही हो जाता है। छारंगर में यह कहावत प्रचलित है, "पुलिसवाले आते-जाते हैं, पर हमारा धंधा सदाबहार है।" राज्य में तो शराब बनायी जाती है ही राज्य के हर उपलब्ध मार्गों-गली, सड़क, रेगिस्तान, जंगल और समुद्री रास्तों से अन्यत्र से भी शराब लायी जाती है।

दक्षिणी गुजरात और सूरत, जो शराबबंदी के कट्टर समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था, की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। वहां भी दिन दहाड़े शराब का व्यापार फलफूल रहा है। यदि अहमदाबाद के नवधनाढ्य शहरियों का स्वर्ग सांझ ढले अपनी कार में लगे स्टीरियो से गजलें सुनते हुए मिलावटी व्हिस्की पीने में है, तो इसी वर्ग के सूरतवासियों की पसंद एक बोतल शराब और ब्ल्यू (नग्न) फिल्म सहित कार से कहीं दूर निकल जाना है। ये दोनों चीजें सूरत में आसानी से उपलब्ध हैं।

एक अनुमान के अनुसार सूरत में ५० हजार लीटर देशी शराब की रोजाना खपत है। इस खपत की २० प्रतिशत आपूर्ति कटरगाम गोटा तलवंडी क्षेत्र का विक्रेता करता है। अंग्रेजी शराब की खपत भी यहां १० हजार बोतल प्रतिदिन है, जो गुजरात के अन्य शहरों से अधिक है। सूरत गुजरात का एकमात्र ऐसा शहर है जहां शराब विक्रेता गर्मी में ठंडी बियर बेचते हैं। यह सुविधा दिल्ली में भी उपलब्ध नहीं है, जहां शराब पर प्रतिबंध लागू नहीं है।

अजीबोगरीब अनुभव: सुबह-सवेरे गांवों से चलकर शहरों की ओर जानेवाली गुजरात राज्य परिवहन की बसों पर सफर करना भी एक अजीबोगरीब अनुभव है। इन बसों के ऊपर मोमजामा, रबर व प्लास्टिक के थैलों, ट्यूबों ब्लाडरों, कनस्तरों आदि में देशी शराब रखी रहती है। इन्हें लानेवाली ज्यादातर महिलाएं होती हैं।

विभिन्न फलों से बनी शराब भी इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। सीमित आपूर्तिवाली यह शराब अपेक्षाकृत महंगी (४० रु० बोतल) हैं। इसे खरीदने के लिए समुद्र तट के गांवों में जाना पड़ता है, क्योंकि यह शहर में नहीं मिलती। सूरत जिले के आदिवासी क्षेत्रों अथवा समीपवर्ती अहवा डांगस में महुए की तेज शराब १५ रुपए प्रति बोतल की दर से मिलती

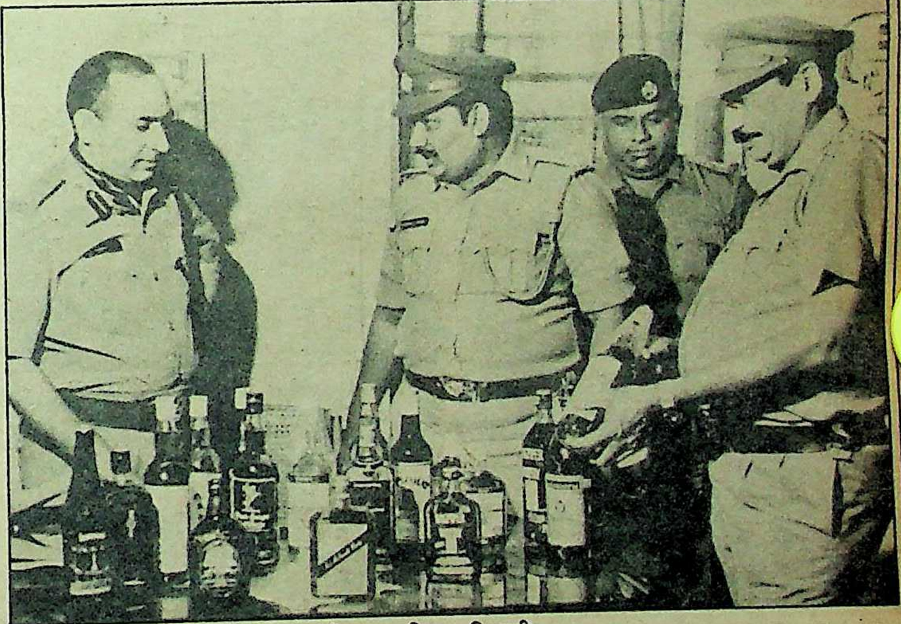

बेअसर छापे: पकड़ी गयी अवैध शराब के साथ पुलिस अधिकारी

है जिसका आधा गिलास ही बेसुध करने के लिए पर्याप्त है। सूरतवासी इसके दीवाने होते हैं।

गुजरात से लगी महाराष्ट्र सीमा से अंग्रेजी शराब की आपूर्ति सूरत में होती है। यदि इन आपूर्ति मार्गों में कोई रुकावट पैदा होती है, तो राजस्थान का उदयपुर शहर इस काम में सहायता देता है। दरअसल, शराब की जरूरतों का एक बड़ा भाग पड़ोसी राजस्थान पूरा करता है। पहले महाराष्ट्र इसकी आपूर्ति करता था, किंतु चतुर गुजराती व्यबसायियों को जब अहसास हुआ कि यह सौदा महंगा है, तो उन्होंने फौरन राजस्थान से तार जोड़ लिया।

बताया जात है कि शराब के कारखाने से निकलनेवाली रद्दी के नाम से मशहूर घटिया शराब को राजस्थान के विभिन्न भागों के थोक व्यापारी खरीद कर पूर्व निश्चित स्थान पर एकत्र कर लेते हैं और उसे चोरी-छिपे गुजरात पहुंचाते हैं। राजस्थान में यह घटिया शराब ३५ रुपए की बोतल की दर से बिकती है। यदि इसमें ५ रुपए ढुलाई और ५ रुपए पुलिस का नजराना जोड़ दिया जाये, तो भी यह ४५

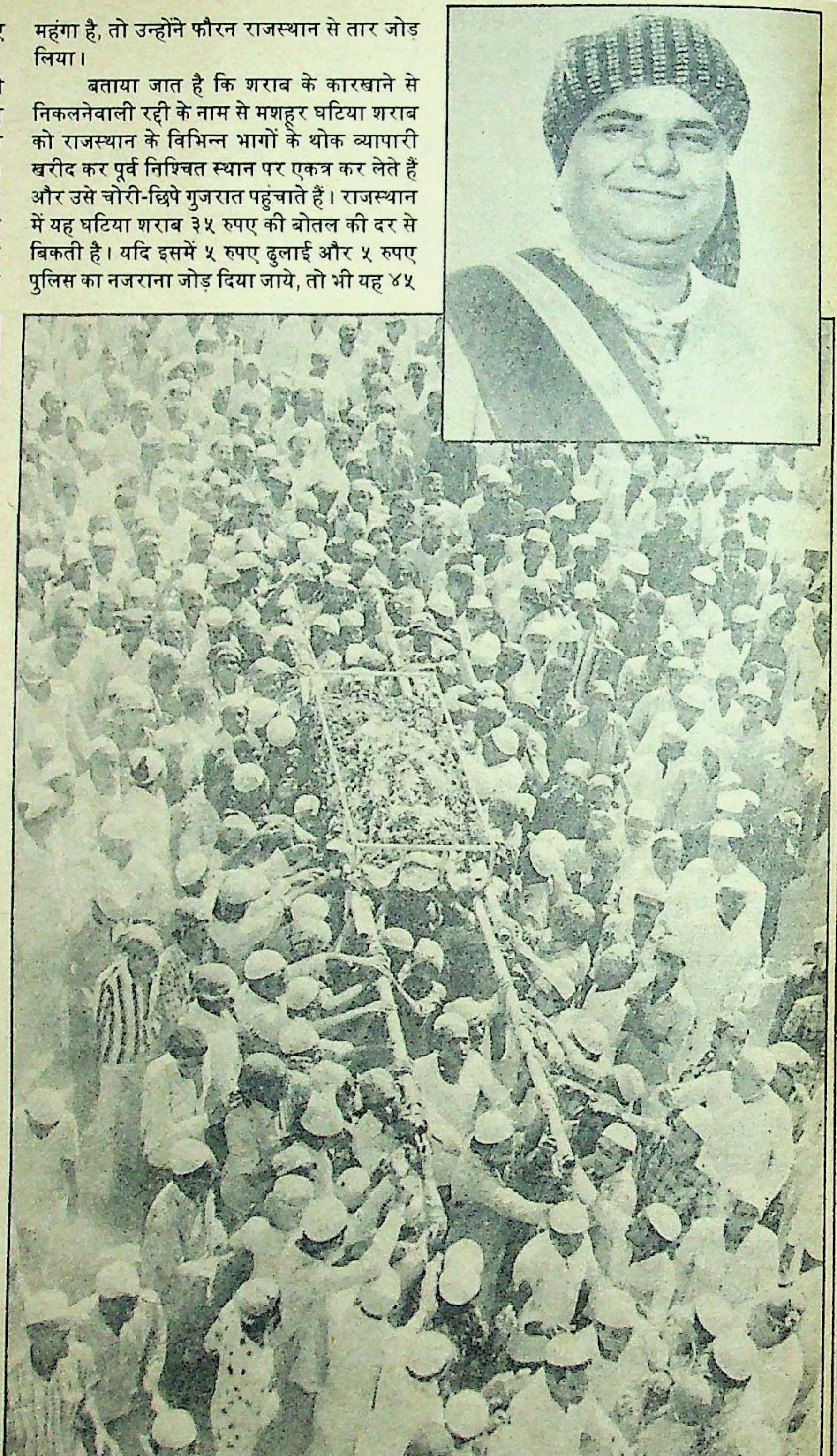

शराब सरगनाओं की लोकप्रियता: अहमदाबाद के नवाब खान (इनसेट) की शवयात्रा

शराबबंदी का इतिहास

सभी प्रमुख धर्मों ने शराब की निंदा किसी-न-किसी रूप में की है। किंतु भारत में ताड़ी, भांग, अफीम और गांजे जैसी नशीली वस्तुओ को एक प्रकार से सामाजिक मान्यता प्राप्त है। किंतु आज भी अधिकांश लोग शराब को एक बुराई ही करार देते हैं। पहले गुजरात में ताड़ी का प्रचलन था। ताड़ी और देसी शराब का सेवन प्रमुखत: आदिवासी, हरिजन, ठाकोर (ठाकुर) व गरासी (राजपूत) करते थे। अंग्रेजी शराब (रम, ह्विस्की, जिन आदि) का गुजरात में प्रयोग उच्च वर्ग व पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोगों तक ही सीमित था। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जिस मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की, उसके चार सूत्रों में एक शराबबंदी भी था। उनके नेतृत्व में गुजरात की शराब की दुकानों का घेराव शुरू हुआ।

१९३७ में जब पहली बार प्रांतीय सरकारें बनी और कांग्रेस अनेक प्रांतों में सत्ता में आयी, तो बंबई राज्य में महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाते हुए शराबबंदी की नीति पर अमल करने का फैसला किया गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब प्रांतों की कांग्रेस सरकारें सत्ताविहीन हो गयीं, तो शराबबंदी की नीति भी समाप्त कर दी गयी। १९४६ में शराबबंदी कानून पास हुआ। १९५० में जब संविधान बना, तो उसकी धारा ४७ में शराबबंदी नीति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

१९५० में सौराष्ट्र और १९५६ में कच्छ में शराबबंदी लागू हुई। १९५६ में सौराष्ट्र व कच्छ को बंबई राज्य में मिला दिया गया। शराबबंदी कानून इस नवगठित राज्य (बंबई) में भी लागू हुआ। द्विभाषी बंबई राज्य का १९६० में विभाजन हुआ, तो मौजूदा महाराष्ट्र व गुजरात राज्य बने। महाराष्ट्र में जहां शराबबंदी में छूट दी गयी, वहीं गुजरात में शराबबंदी कागज पर आज भी लागू है।

रुपए बोतल ही पड़ती है, जबकि अहमदाबाद में यही शराब ८० रुपए बोतल के हिसाब से बिकती है। इस प्रकार शराब विक्रेता को ३५ रुपए प्रति बोतल मुनाफा होता है।

गुजरात में रद्दी वाले शराब की खाली बोतलें खरीदने मे विशेष दिलचस्पी दिखाते हैं। ये बोतलें शराब विक्रेता अधिक दामों में खरीद लेते हैं। इनमें मिलावटी शराब, खासकर व्हिस्की, जिसका गुजरात में बहुत प्रचलन है, भरी जाती है। इस शराब की कुल लागत १५ रुपए बोतल आती है और इसे ५० से ८० रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बेचा जाता है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि करोड़ों रुपए का यह विशाल अवैध धंधा पुलिस की निरापद छत्र-छाया में ही राज्य में फल-फूल रहा है। जगजाहिर है कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें, गुजरात पुलिस के उच्चाधिकारियों तक फैली हैं। यही कारण है कि कानून-व्यवस्था कायम करनेवाले इस विभाग में अनुशासन का पूरी तरह अभाव दिखाता है। स्थिति यह है कि बुरे आचरण के लिए गिरफ्तार किया गया शराबी यदि शराब विक्रेता का नाम बता देता है, तो उसकी जमानत की व्यवस्था खुद पुलिस शराब विक्रेता के माध्यम से करा देती है।

मिलीभगत: राज्य में पुलिस और शराब विक्रेताओं की मिलीभगत का भांडा तब फूटा जब १८ अगस्त, १९८८ को सीबीआई ने अहमदाबाद में विशेष पुलिस महानिरीक्षक (अपराध व रेलवे) के एच भाया के आवास व कार्यालय पर छापा डालकर क्रमश: १९ लाख व ५.३ लाख रुपए बरामद किये। दिल्ली से आये सीबीआई अधिकारियों को पता चला कि भाया व उनके परिवार के नाम से ३१ बैंक एकाउंट हैं और एक दर्जन से ज्यादा बैंक लाकर (तिजोरियां) हैं। अनुमान है कि उनकी कुल चल-अचल संपत्ति एक करोड़ रुपए से अधिक की हैं। यह छापा उनकी सेवामुक्ति के एक महीने पूर्व डाला गया था। सीबीआई को एक डायरी और कुछ ऐसे कागजात भी मिले जिनमें पुलिस अफसरों से तबादले के लिए ली गयी रकमों का ब्यौरा था। गुजरात में ऐसे अनेक पुलिस उच्चाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने थोड़े समय में काफी कमाई की है।

भाया के घर पर पड़े छापे के चंद घंटों के दौरान गुजरात के एक महत्वपूर्ण शहर में सेवारत एक आला पुलिस अफसर, एक इंसपेक्टर को अपने साथ लेकर बंबई भागे थे। अचानक वे बंबई क्यों गये और अपने साथ क्या ले गये ? यह आज तक रहस्य है। बताया जाता है कि उन्होंने मारुति की डीलरशिप में परदे के पीछे का साझीदार बनने के लिए ५० लाख रुपए लगाये थे। इतनी बड़ी रकम उन्हें कहां से और कैसे प्राप्त हुई ? यह किसी को नहीं पता।

इसी तरह एक पुलिस उच्चाधिकारी ने बड़ौदा के गोत्री क्षेत्र की ८९०० वर्गफुट भूमि ९० रुपए प्रति वर्गफुट की दर से हिंदी फिल्मों में मां की भूमिका करने के लिए विख्यात बंबई की अभिनेत्री से खरीदी। यही नहीं, गुजरात में तैनात एक पुलिस अधिकारी देखते-देखते दिल्ली के आलीशान इलाके पंचशील पार्क के एक बंगले का मालिक बन गया। उल्लेखनीय है कि पंचशील पार्क में जमीन की कीमत २५ हजार रुपए प्रति वर्ग गज है।

जानकार सूत्रों के अनुसार गैरगुजराती पुलिस अधिकारी अपनी ऊपरी कमाई को राज्य के बाहर, खासकर अपने गृह नगर में होटल आदि जैसे लाभकारी निर्माण में लगाना पसंद करते हैं और स्थानीय पुलिस अधिकारी बड़ौदा और सूरत में अपनी पूंजी लगाते हैं। बताया जाता है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने २५ लाख रुपए की साझेदारी करके बिजली करघा उद्योग में हिस्सा हासिल किया था।

यही नहीं, अहमदाबाद में तैनात एक अन्य पुलिस उच्चाधिकारी ने बड़ौदा के करेलीबाग क्षेत्र के अपने बंगले को किराये पर उठाने के लिए अपने एक कनिष्ठ अफसर की मदद मांगी थी। कहा जाता है कि वे ७००० रुपए माहवारी किराये के इच्छुक थे।

एक अन्य सूत्र के अनुसार गुजरात पुलिस को अवैध शराब की बिक्री और जुए से भारी कमाई होती है। प्रत्येक थाने का 'हफ्ता' बंधा हुआ है। अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार तो गुजरात पुलिस शराब विक्रेताओं से कम-से-कम ५०० करोड़ रुपए सालाना वसूल करती है। आमदनी के मुख्य केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत व बुलसार हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश सर्वाधिक संख्या में सूरत में लिये जाते हैं। इस क्रम में पुलिस थाने के एक प्रभारी निरीक्षक का उल्लेख करना जरूरी है। बताया जाता है कि अहमदाबाद के एक थाने के प्रभारी निरीक्षक, जिसकी हाल में पदोन्नति करके तबादला किया गया है, के शहर के आलीशान इलाके की आठ निर्माण कंपनियों में प्रमुख साझे हैं। साथ ही वे १० हजार वर्गगज से अधिक के ११ भूखंड, ४ कारें, २ रेफ्रिजरेटर, चार एयरकंडिश्नर और ७ कमरोंवाले एक बंगले के मालिक भी हैं।

सिर से पैर तक भ्रष्टाचार: पुलिस विभाग में ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में स्थानीय राजनीतिज्ञों की भी मिलीभगत रहती है। ऐसी स्थिति में कानून का कड़ाई से पालन करने और रिश्वत न लेनेवाले ईमानदार पुलिस अधिकारियों को परेशानी, अपमान, दंड का भागीदार बनना पड़ता है। विभाग में फैली अव्यवस्था, गुटबंदी और निहित स्वार्थों की गूंज १९७९ के पुलिस विद्रोह में सुनायी पड़ी थी। उस समय पुलिस की अलग-अलग यूनियनें विधायकों और मंत्रियों से सीधी बातचीत में लगी थीं।

यही कारण है कि कानून और व्यवस्था की मशीनरी समाज विरोधी तत्वों और राजनीतिज्ञों के हाथों का खिलौना बन गयी है। नतीजतन गुटीय,

असामाजिक तत्वों की गिरफ्त

गुजरात सरकार ने १९८१ में मियां भाई आयोग का गठन इस उद्देश्य से किया था, ताकि पता चल सके कि गुजरात में शराबबंदी की मुहिम कामयाब क्यों नहीं हुई ? मियां भाई आयोग ने अपने अध्ययन के बाद १९८३ में जो रिपोर्ट पेश की, उसमें साफ कहा गया था कि मुहिम के विफल होने का एकमात्र कारण व्यापक पैमाने पर फैला हुआ भ्रष्टाचार और वे समुदाय हैं, जो शराब की लत से बुरी तरह ग्रस्त हैं।

आयोग ने शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के अपने सुझाव में कहा था कि जिन मुद्दों पर उसे अपने सुझाव पेश करने को कहा गया था, उसमें राज्य में मौजूदा शराबबंदी नीति को समाप्त करना शामिल नहीं था। शराब विक्रेताओं के तंत्र का उल्लेख करते हुए आयोग ने कहा कि अनगिनत असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर गैरकानूनी शराब की ढुलाई और वितरण करते हैं।

शराब विक्रेताओं के मुनाफे के बारे में आयोग ने पुलिस अफसरों के बयानों के आधार पर स्पष्ट किया कि मुनाफा लागत से ९ से १२ गुना अधिक होता है और राज्य में इससे अधिक मुनाफेवाला कोई दूसरा धंधा नहीं है।

शराब विक्रेताओं व राजनीतिज्ञों की गठजोड़ के बारे में मियां भाई का मत है कि काली कमाई के बलबूते शराब विक्रेताओं ने सम्मान अर्जित करने के साथ-साथ राज्य के सामाजिक व राजनीतिक लोगों का सहयोग भी हासिल कर लिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शराब के धंधेबाजों का दूसरे अपराधों से भी घनिष्ठ संबंध है और स्थानीय पुलिस का शराब विक्रेताओं से तालमेल है। इस संबंध में रिपोर्ट में आगे लिखा है कि राज्य में शायद ही कोई ऐसा पुलिस थाना हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। भ्रष्ट तत्वों का राजनीतिक सत्ता से संबंध होने के कारण ईमानदार पुलिस अधिकारी भी कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाते और यदि कोई हिम्मत करता है, तो उसका फौरन तबादला कर दिया जाता है।

■

जातीय और सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। नौबत यह है कि बड़ौदा में पुलिस आयुक्त के समर्थन में दंगा हुआ। इसी प्रकार अहमदाबाद में प्रेस के विरोध में आगजनी की वारदात हुई और पुलिसजनों ने 'गुजरात समाचार' का कार्यालय फूंक दिया। ये घटनाएं ही अंततः सोलंकी सरकार के पतन का कारण बनी थीं। उन्हीं संगीन हालात में अमर सिंह चौधरी ने राज्य की बागडोर संभाली। फिर रातोरात दिल्ली से जेएफ रिबेरो को राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाकर भेजा गया, जिससे स्थिति में कुछ दिन के लिए सुधार आया।

बाद में मनमोहन सिंह को गुजरात पुलिस का इंचार्ज बनाया गया। अपनी ईमानदारी, परिश्रम, कार्यकुशलता व मुंहफटपन के लिए विख्यात सिंह को समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारी परेशान करते रहते हैं और अकसर मौकों पर उन्हें अपमानित होना पड़ता है। किंतु सचाई यह है कि उनके कार्यकाल में प्रच्छन्न विरोध के बावजूद कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पुलिस अनुशासनहीनता पर रोक लगी है और पुलिस यूनियनों को भंग कर दिया गया है। सिंह की एक अहम उपलब्धि यह है कि उन्होंने राज्य में शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी से पुलिस को मुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी दे दी है। जाहिर है, इस कदम से भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण खतम हो जायेगा। सरकार भी शराबबंदी के इस काम पर अमल कराने के लिए एक अलग संगठन बनाने को सोच रही है। किंतु इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

इलाज क्या है ? : गुजरात में शराब का धंधा पिछले दशक में जिस तेजी से पनपा है, उसको पलक झपकते ही खतम कर देना तो आसान बात नही है, किंतु ईमानदार और परिश्रमी पुलिस अधिकारी इस पर अंकुश जरूर लगा सकते हैं। पिछले एक दशक में यह देखा गया कि जब-जब इस राज्य में ईमानदार पुलिस अधिकारी तैनात हुए, अवैध धंधे पर कुछ-न-कुछ अंकुश जरूर लगा। किंतु विडंबना यह है कि ईमानदार अधिकारी राज्य में ज्यादा दिन ठहर नहीं पाते, क्योंकि सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे पुलिस और राजनीतिक तंत्र को साल-छह महीने में बदलना आसान बात नहीं है। फिर इस धंधे से करोड़ों रुपए की धन-उगाही कर चुके शराब विक्रेताओं के हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि जो अधिकारी इन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है वह स्वयं इनके आक्रोश का निशाना बन जाता है। साथ ही, पुलिस मशीनरी भी इस धंधे पर अंकुश लगाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उच्च अधिकारियों को उनका सहयोग नहीं मिलता। वजह सिर्फ यह है कि अरसे से जो अवैध कमाई हो रही है, जिसके फलस्वरूप मामूली-सा थाना प्रभारी भी आलीशान बंगलों का मालिक बन गया है, उसे वे बंद नहीं करवाना चाहते। इसलिए गुजरात की समस्या का इलाज सिर्फ ईमानदार उच्च अधिकारियों को तैनाती करने से हल नहीं हो सकती, बल्कि सरकार को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा।

इसमें संदेह नहीं कि मनमोहन सिंह ने गुजरात की बागडोर संभालकर काफी सुधार किये। किंतु कुछ ऐसा नहीं हो सका है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि गुजरात में अब तक शराब की जो गंगा बह रही थी वह सूख चली है या उसका रुख मोड़ दिया गया है। फिर मनमोहन सिंह भी तो चंद महीनों में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।

फिलहाल गुजरात में इस विषय पर बहस छिड़ी हुई है कि शराबबंदी में छूट दी जानी चाहिए यां इसे पूर्णतः खतम किया जाना चाहिए। जो लोग शराबबंदी के विरोधी हैं, उनका मानना है कि शराबबंदी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है और मानव अधिकार पर सीधा हमला है। वे यह भी तर्क देते हैं कि शराबबंदी लागू करने पर भी शराब की बिक्री रुकती नहीं है, बल्कि महंगी, मिलावटी और जहरीली शराब का धंधा पनपता है। शराबबंदी विरोधी आर्थिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह भी कहते हैं कि शराबबंदी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम राजस्व में घाटा होना है।

बहरहाल, शराबबंदी उचित है या अनुचित बहस यह नहीं, सवाल तो यह है कि गुजरात में पनपे शराब के अवैध धंधे पर अंकुश कैसे लगे जिसने महात्मा गांधी की जन्मभूमि वाले राज्य को भ्रष्टाचार और हिंसा का राज्य बना दिया है। यद्यपि राज्य में शराबबंदी लागू हुए लगभग चार दशक बीत चुके हैं, किंतु इतने वर्षों में अब तक कोई ठोस सुधार नहीं आया है।इतना जरूर है कि शराबबंदी पर अमल कराने के लिए एक अलग संगठन बनाये जाने से पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूर लग सकता है, वह भी तभी जब सरकार अपने इस वायदे पर अमल करे।

—आरके मिश्रा

घर-घर शराब बनाने का धंधा

अहमदाबाद के समीप छारंगर में झुग्गी-झोंपड़ियों की एक घनी बस्ती है जहां के ६० प्रतिशत लोग गैरकानूनी शराब बनाने के धंधे में लगे हैं । उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश छारस आदिवासी हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासकों ने अपराधी करार देकर १६२६ में यहां बसा दिया था। अनेक दशकों से ये शराब बनाने का काम करते आ रहे हैं। ये आदिवासी मेवाड़ से यहां आये थे। इनमें से कुछ १६२२-२३ में अहमदाबाद में चंद्रभागा पुल के सामने बस गये थे। उस क्षेत्र में चोरी की अनेक वारदातें होने के बाद उन्हें वदाज क्षेत्र में बसा दिया गया। किंतु इनकी गतिविधियों में परिवर्तन न आने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें वहां से हटाकर छारंगर इलाके में बसाया। तब से इन्हें अपराधी जाति का करार दिया जाता था। १६७२ में बख्शी आयोग ने इन्हें पिछले वर्ग की श्रेणी में शामिल किया। शराब बनाने के अलावा इनका दूसरा पेशा आज भी चोरी करना है। इनमें से कुछ लोग व्यापार में भी लगे हैं।

इस इलाके में प्रवेश करते ही शराब की तीखी गंध का अहसास होता है। शराब बनाने के काम में ज्यादातर महिलाएं लगी होती हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें हाथ बंटाते हैं। महिलाओं के आगे रहने का कारण यह है कि पुलिस उनसे नरमी से पेश आती है। जानकार सूत्रों के अनुसार प्रत्येक परिवार ५०० से १००० रुपए प्रति माह पुलिस को रिश्वत भी देता है। ■

एक तीखी रिपोर्ट

सरदार पटेल आर्थिक व सामाजिक शोध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार शराबबंदी पर अमल करने से गुजरात में गरीबों का भी कोई भला हुआ है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार—जिसने संस्थान को लगभग एक दशक पूर्व यह अध्ययन कार्य सौंपा था—ने इस तीखी रिपोर्ट को दबाने की भरपूर कोशिश की। इसे छापने की अनुमति भी नहीं दी गयी। इसकी महज एक प्रति संस्थान के पुस्तकालय में मौजूद है।

अध्ययन का विषय था शहरी गरीबों में शराब का प्रचलन और उसका आर्थिक प्रभाव। अध्ययन के अनुसार शराब पीने से कमाई पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि खाने-पहनने आदि की वस्तुओं पर खर्च न करके शराब पर खर्च किया जाता है। यदि शराब के खर्च को बंद करके उसे खाने-पहनने के खर्च में बदल दिया जाये, तो भी गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी।

अध्ययन में आगे कहा गया है कि शराब की बेरोकटोक बिक्री पर रोक लगाना शायद जरूरी है। किंतु नशेड़ियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती शराब उपलब्ध होनी चाहिए। नौजवानों व गरीबों को जहां शराब से बचाना चाहिए, वहीं शराब सेवन करनेवाले अमीरों से अधिक राजस्व वसूलने का प्रयास होना चाहिए। ■

मेरी दुनिया ही पलट जाती...

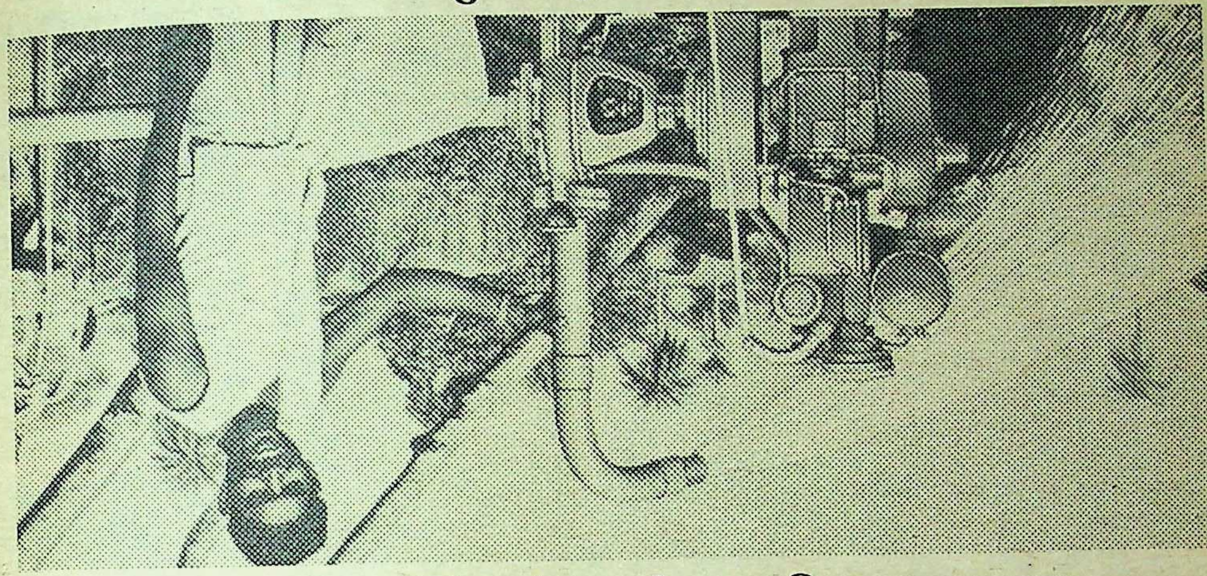

अगर मैं न्यू इन्डिया से पम्पसेट का बीमा न करवाता.

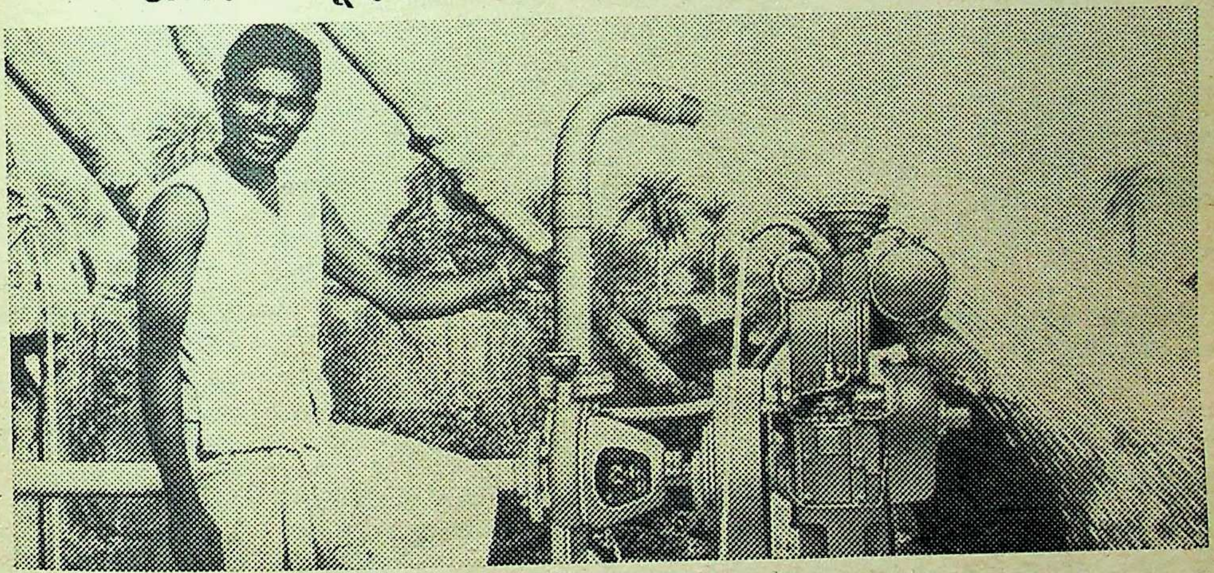

मेरा पम्पसेट चोरी हो गया लेकिन काम नहीं रुका, क्योंकि न्यू इन्डिया की बदौलत मैं नया पम्पसेट लगवा सका.

एक किसान के लिए उसका पम्पसेट कितना मूल्यवान होता है, यह बात वह और उसके परिवारवाले अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन वही पम्पसेट अगर जल जाए, टूट जाए, बिगड़ जाए ... या चोरी हो जाए तो? ऐसे में, न्यू इन्डिया एश्योरन्स एक सच्चे मित्र की तरह उसका सहारा बनता है.

पम्पसेट बीमा – न्यू इन्डिया एश्योरन्स का मोटर के हॉर्स पावर के हिसाब से सालभर में 50 रुपए से 190 रुपए तक देने पड़ते हैं... बस! देशभर में न्यू इन्डिया एश्योरन्स के लगभग 1000 कार्यालय हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही एजेंट से मिलें या अपने नज़दीकी कार्यालय में पधारें.

न्यू इन्डिया एश्योरन्स

जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी

पम्पसेट बिमा – नुकसान में आपका सहारा!

R K SWAMY/NIA/3573B/HIN R

कौन किस पर हंस रहा है ? : तारिक अनवर और भागवत झा आजाद

कामराज के संस्करण : सीताराम केसरी

प्रदेश अध्यक्ष : डा० जगन्नाथ मिश्र

अचानक तख्तापलट का राज

राजीव गांधी के वर्चस्व को जबर्दस्त चुनौती देनेवाले बिहार के संकट को हल करने के लिए इंका आलाकमान ने 'कामराज योजना' की तर्ज पर जो 'केसरी योजना' लागू की, उसके पीछे मजबूरी क्या है और आगे संभावनाएं क्या हैं ? छह साल की घोर उपेक्षा के पात्र डा० जगन्नाथ मिश्र को बिहार प्रदेश कांग्रेस-इ का अध्यक्ष बनाये जाने के पीछे कोई लाचारी है या रणनीति ? संशय और असमंजस की स्थिति के दौरान बिहार में कांग्रेस के कौन अंतर्विरोध उभरे हैं ?

यह एक अद्भुत नाटक था। उसमें पूरे एक दर्जन पात्र थे। बड़े से लेकर छोटे तक। किसी को यह पता नहीं था कि अगले क्षण मंच पर चढ़कर उसे कौन-सी भूमिका निभानी है। लिहाजा, मंच से नीचे उतरकर सबके सब दम साधे खड़े थे। "मैं तो इस नाटक का एक पात्र भर हूं। क्या कह सकता हूं, क्या होगा ?" बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने ४ मार्च की रात ग्यारह बजे उन पत्रकारों से कहा जो उनके इस्तीफे और उसके बाद की संभावनाओं के बारे में जानने को बेचैन थे। उस समय आजाद मोकामा में पदयात्रा और जनसभा करके बस पटना पहुंच ही रहे थे। उनकी सफेद सरकारी एंबेसडर जब पोर्टिको में रुकी, तो घंटों से प्रतीक्षारत भीड़ ने उन्हें घेर लिया। शाम सात बजे से ही मुख्यमंत्री निवास में भीड़ जमनी शुरू हो गयी थी। मुख्यमंत्री मोकामा में थे। मुख्यमंत्री निवास का वायरलेस हर पांच मिनट पर पूछ रहा था, "मुख्यमंत्री पटना कितनी देर में पहुंच रहे हैं ?"

केसरी का कमाल: "पूरे बिहार में, विशेषकर पटना के राजनीतिक गलियारों में, अचानक उस शाम सनसनी मच गयी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय खजांची सीताराम केसरी के हवाले से दिल्ली से यह खबर जारी हुई कि पिछले डेढ़ महीने से चले आ रहे बिहार के राजनीतिक संकट के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री आजाद, बिहार के सभी सात केंद्रीय मंत्रियों (बिंदेश्वरी दुबे, ललितेश्वर प्रसाद शाही, केके तिवारी, कृष्णा शाही, रफीक आलम, डुमरलाल बैठा तथा सुमति उरांव) सहित कांग्रेस के खजांची पद से सीताराम केसरी, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से तारिक अनवर और यहां तक कि बिहार से लिये गये कांग्रेस के दो राष्ट्रीय संयुक्त सचिवो (सरफराज अहमद व फगुनी राम) ने एकमुश्त त्यागपत्र आलाकमान के सिपुर्द कर दिया है और कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का हर फैसला उन्हें मान्य होगा। ४ मार्च की शाम दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय २४ अकबर रोड में सीताराम केसरी इस सामूहिक इस्तीफे की खबर पत्रकारों को दे रहे थे। कायदे से जहां यह खबर बिहारी मामलों के प्रभारी महासचिव आस्कर फर्नांडीस को जारी करनी चाहिए थी, वहां स्वयं इस्तीफा दिये बैठे केसरी यह जिम्मेदारी निभा रहे

इस्तीफा : बायें से श्रीमती कृष्णा शाही, बिंदेश्वरी दूबे, केके तिवारी, ललितेश्वर प्रसाद शाही

थे। पत्रकारों ने केसरी से सवाल किया कि ये इस्तीफे प्रधानमंत्री के निर्देश पर दिये गये हैं या बिहार के नेताओं ने ऐसा अपनी मर्जी से किया है? केसरी का जवाब था, "सभी बुद्धिमान सदैव एक जैसी ही बात सोचते हैं। यह फैसला स्वयं बिहार के नेताओं ने एकमत से लिया है।" साथ ही केसरी ने यह भी कहा कि ड़ा० जगन्नाथ मिश्र ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उनका 'बिहार जनविकास मंच' भारत सेवक समाज जैसा एक गैर-राजनीतिक संगठन है और कहा है, "आलाकमान के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है। बिहार के बारे में वे चाहे जो फैसला लें वह मुझे मान्य होगा।"

केसरी के प्रेस कांफ्रेंस के ठीक एक घंटे पूर्व एक समाचार एजेंसी ने यह खबर जारी की कि डा० जगन्नाथ मिश्र का नाम अगले मुख्यमंत्री के रूप में जोर पकड़ रहा है। पत्रकारों ने पलट कर जब इस खबर की बाबत पूछा, तो केसरी ने संक्षिप्त टिप्पणी की—"अब सबकुछ आलाकमान की अदालत में है।" ४ मार्च को डा० जगन्नाथ मिश्र मगध एक्सप्रेस से पटना आ चुके थे। पटना में उन्हें भी शाम को पता चला कि केसरी ने उनका भी जिम्मा लेकर बयान दिया है। अपने इस्तीफे के बारे में कई केंद्रीय मंत्री तक अनभिज्ञ थे। इस्तीफे की घोषणा के दिन कई मंत्री दिल्ली से बाहर भी थे। केसरी के प्रेस कांफ्रेंस के बाद जब कुछ पत्रकारों ने केंद्रीय राज्यमंत्री केके तिवारी के निवास पर फोन करके उनके इस्तीफे की पुष्टि करनी चाही, तो तिवारी के कारिंदे एकबारगी चौंक पड़े, क्योंकि तिवारी हज कमेटी की एक बैठक के सिलसिले में एक दिन पूर्व ही रियाद चले गये थे। लिहाजा, तिवारी के मुलाजिमों ने फौरन रियाद फोन मिलाकर तिवारी को उनके इस्तीफे की घोषणा के बारे में सूचना दी। ५ मार्च को तिवारी दिल्ली आ गये।

बदलते दिन : भीष्म नारायण सिंह

प्रतियोगिता में : लहटन चौधरी

नेता मायूस : बिहार के राजनीतिक उपद्रव को समाप्त करने के लिए सामूहिक इस्तीफे के इस फार्मूले ने राजनीति के तमाम बिहारी दिग्गजों को सांसत में डाल दिया।

अपनी पार्टी में भीषण बगावत के बाद २० फरवरी को पहली बार राजीव गांधी ने बिलकुल दहाड़कर जब यह कहा कि पार्टी में विक्षुब्ध गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी, तो एकबार अटकलें गर्म हो गयीं कि शायद आजाद बरकरार रह जायें। २२ फरवरी को राजीव गांधी ने कहा कि जगन्नाथ पहाड़िया के बिहार के राज्यपाल बन जाने से कांग्रेस कमेटी में महासचिव का एक पद रिक्त हुआ है, साथ ही एक और महासचिव की आवश्यकता है। इसलिए शीघ्र ही दो महासचिव मनोनीत किये जायेंगे। पटना में बैठे राजनीतिक पंडितों का खयाल था कि शायद डा० जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस महासचिव बना दिये जायें। दिल्ली के साउथ ब्लाक में फिर आरके धवन के आ जाने से भी जगन्नाथ समर्थकों की आशा बंधी थी कि शायद धवन दिल्ली दरबार से जगन्नाथ की कटी डोर ठीक से जोड़ दें। इंदिरा गांधी के जमाने से ही धवन से जगन्नाथ मिश्र के मधुर संबंध रहे हैं। पर मिश्रा के महासचिव बनने की अटकल भी तब गलत साबित हो गयी जब ६ मार्च को यह घोषणा हुई कि चुनाव तक कांग्रेस कमेटी में कोई हेरफेर नहीं होगा। साथ ही पहाड़िया के रिक्त स्थान पर संयुक्त सचिव एआर मल्लू को महासचिव पद पर प्रोन्नत कर बिहार के मामलों का प्रभारी बना दिया गया। कांग्रेस खजांची पद से सीताराम केसरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह कांग्रेस कमेटी में हुए इस मामूली परिवर्तन ने इस्तीफा देकर बैठे बिहार के नेताओं को मायूस कर दिया।

एक कुरसी, अनेक नाम : बहरहाल, केंद्र से प्रांत तक बिहार का सामूहिक तख्तापलट कराने के फार्मूले को चलाकर केसरी रातोरात राजीव युग के स्वयंभू कामराज हो गये। सामूहिक तख्तापलट की घोषणा करते हुए केसरी ने कहा भी, "अब आप देखेंगे केसरी की टंकार।" सामूहिक तख्तापलट का चक्कर चलाकर केसरी ने अपने कई राजनीतिक दुश्मनों से बदला भी चुका लिया, यहां तक कि अपने पुराने शागिर्द तारिक अनवर से भी। इस्तीफे की घोषणा के बाद भावी मुख्यमंत्री को लेकर संभावित नामों की चर्चा जोर-शोर से चालू थी। बिंदेश्वरी दुबे तो इस दौड़ से बहुत पहले ही बाहर हो चुके थे। इस्तीफे के बाद तो यह चर्चा गर्म हो गयी कि बागियों को शह देने की सजा के तौर पर दुबे को राज्यपाल पद थमा कर स्थायी रूप से राजनीतिक बनवास दे दिया जायेगा। केंद्रीय राज्यमंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही भी शुरू में अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी सक्रिय थे। पर दुबे के बाद इस दौड़ में पिछड़नेवाले शाही ही थे। बहरहाल, अब असम के राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह, डा० जगन्नाथ

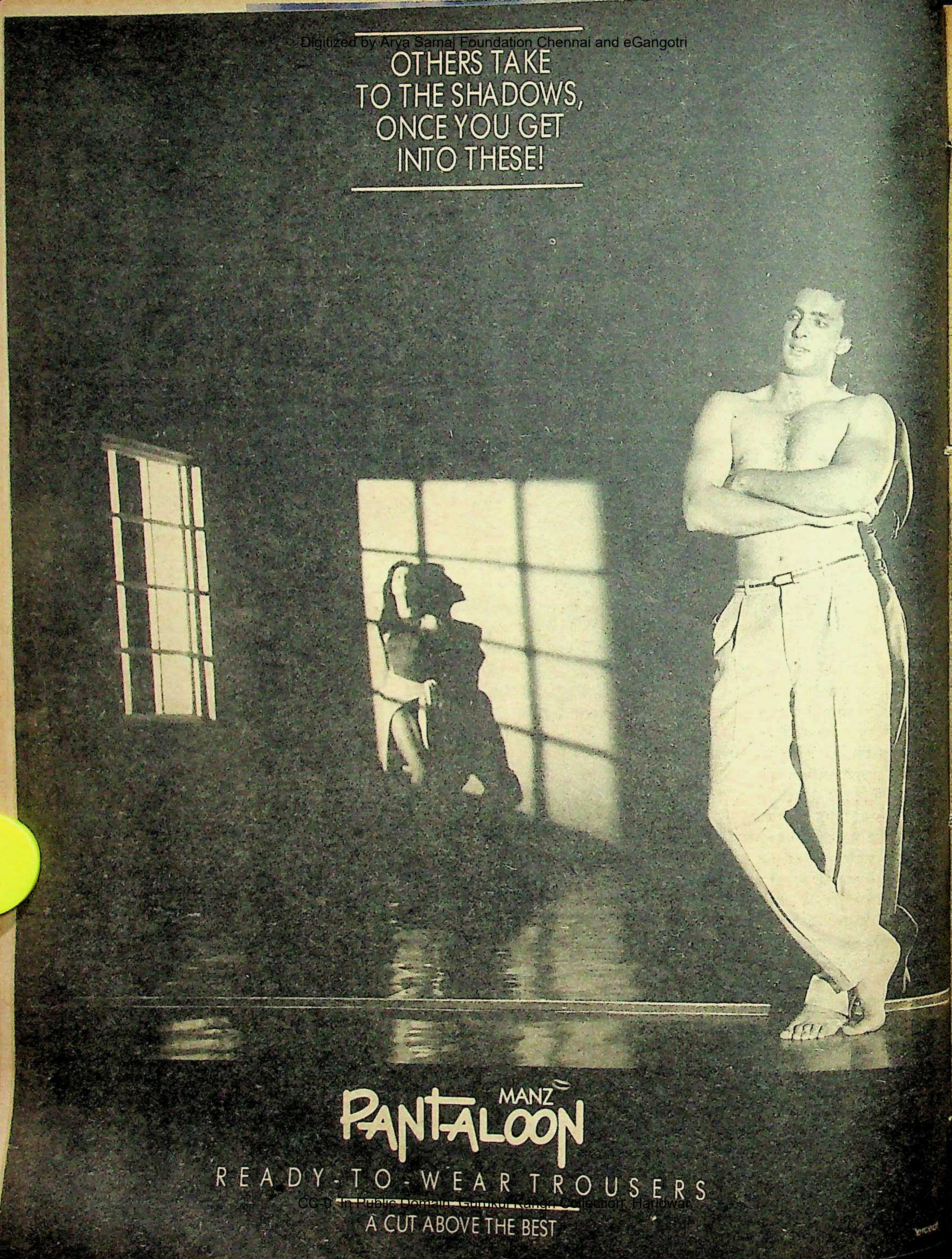
OTHERS TAKE
TO THE SHADOWS,
ONCE YOU GET
INTO THESE!
MANZ
PANTALOON
READY-TO-WEAR TROUSERS
A CUT ABOVE THE BEST

मिश्र तथा आजाद मंत्रिमंडल में सिंचाई विभाग के काबीना मंत्री लहटन चौधरी का नाम फेहरिस्त में बच गया। पर भीतर ही भीतर केसरी इन तीनों नामों को खारिज करने की रणनीति में जुटे थे। भीष्म नारायण सिंह से केसरी की शत्रुता उन्हीं दिनों से रही है जब भीष्म नारायण श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री थे और केसरी उनके विभाग में राज्यमंत्री थे। केसरी की सदैव अपने इस काबीना मंत्री से ठनी रहती थी। केंद्रीय राजनीति से भीष्मनारायण सिह को चलता करने की मुहिम में केसरी सर्वाधिक सक्रिय रहे थे। इसलिए जब बिहार के मुख्यमंत्रीपद हेतु भीष्म का नाम फिर आ रहा था, तो केसरी परेशान थे। भीष्म नारायण सिह के बारे में दिल्ली दरबार को यह बताया गया कि न तो राजपूतों पर उनका प्रभाव है न ही प्रदेश की राजनीति से कभी उनका सरोकार रहा है, सो चुनावी संघर्ष की लगाम भी भीष्म नहीं संभाल पायेंगे। इस तरह भीष्म को काटने के बाद अब केसरी ने अचानक नारा दिया कि बिहार में पिछड़ी जाति को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जानी चाहिए। केसरी का तर्क था कि हरिजनों व पिछड़ों की तरफदारी के बावजूद जनता दल ने मैथिल ब्राह्मण रघुनाथ झा को प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया जिससे बिहार की पिछड़ी जाति जनता दल से नाराज है, ऐसे में अगर कांग्रेस पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बिहार में बिठाती है, तो स्व० कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में पिछड़ों की राजनीति में व्याप्त खालीपन का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। केसरी के इस तर्क के साथ ही पिछड़ी जाति के लहटन चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ गया। केसरी ऐसा चाहते भी थे। केसरी का एक राजनीतिक फार्मूला यह भी रहा है कि जिस नाम को कटवाना हो, उसे जोर से पहले उछाल दिया जाये। नतीजतन, उस नाम का धुआंधार विरोध शुरू हो जायेगा और आखिरकार वह नाम 'रेस' से बाहर हो जायेगा। ऐसा ही हुआ भी। लहटन के खिलाफ तमाम नेता जुट गये और उनसे संबंधित कई पुराने विवादास्पद मामले आनन-फानन बटोर कर पेश करने लगे। ब्राह्मणों में एकमात्र मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी जगन्नाथ मिश्र का नाम स्वयं केसरी ने पहल कर उछाला। ६ मार्च को केसरी ने दिल्ली के चुनिंदा अखबारों में काफी प्रयास कर यह खबर छपवायी कि मजबूर होकर आलाकमान जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुका है। इस खबर का तात्कालिक प्रभाव तो यह हुआ कि जगन्नाथ मिश्र के पटना स्थित निवास २, सर्कुलर रोड पर ७ मार्च की सुबह से भीड़ उमड़ पड़ी। पर जगन्नाथ मिश्र अपने लोगों से कह रहे थे कि किसी ने यह खबर छापकर उनसे दुश्मनी निकाली है। अगर उनका नाम विचाराधीन था भी, तो पहले ही इस तरह की खबर देना उसे खतम करवाने की ही कोशिश थी। केसरी जब फिर बिहार में पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री भेजे जाने के फार्मूले को हवा देने लगे, तब स्पष्ट हो गया कि इस फार्मूले के तहत वे अपनी ही उम्मीदवारी की गोट जमा रहे हैं। दिल्ली के एक दिग्गज राजनीतिक खिलाड़ी ने ७ मार्च की रात 'माया' से कहा, "शुरू में यह बात संकोचवश मैं किसी से नहीं कह पा रहा था कि केसरी भी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। शायद मेरी यह बात सुनकर लोग मेरी बुद्धि पर हंसें। पर अब मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि केसरी शुरू से आखिर तक बस इसी मुहिम में लगे रहे हैं।"

४ मार्च की रात से ही पटना हवाई अड्डे पर पर्यवेक्षकों से लदे विमान के उतरने की अपेक्षा पटना के राजनीतिक जीवजंतु कर रहे थे। पर दिन पर दिन बीत रहे थे, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही थी। इसलिए एक बार फिर यह संभावना बलवती होने लगी कि शायद आजाद फिर दूनी ताकत से टिका दिये जायें। ५ मार्च की दोपहर मुख्यमंत्री निवास में नये राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के सम्मान में भोज का आयोजन था। आम दिनों की भांति मुख्यमंत्री आजाद पार्टी में प्रफुल्लित भाव से मेहमानों की अगवानी कर रहे थे। वहां पहुंची पत्रकारों की टोली में से कुछ ने सवाल किया, "बिहार में नयी सरकार कब बन रही है?" आजाद ने तपाक से कहा, "शुक्र है, अभी तक आप यह तो स्वीकार रहे हैं कि पुरानी सरकार गयी नहीं है।"

—विकास कुमार झा

Get your
PANTALOON
at:

EAST ZONE

CHASE — Maurya Lok, Patna AKASH GANGA — Boring Road, Patna THE RIGHT SHOP — G.S Road, Shillong BROADWAY COLLECTIONS — G.S Road Shillong JACKPOT SALES — Paone Bazar, Imphal SAPPHIRE — Bapuji Nagar, Bhubaneshwar SAMRAT — Kumar Patty, Guahati

WEST ZONE

WARDROBE — Sadar Nagar Nagpur SIROCCO — M.G Road Pune BHARAT WOOLLEN HOUSE — Laxmi Road, Pune KANCHAN DRESS CENTRE — Deccan, Pune KRI-ME — Shahibaugh, Ahmedabad R' AV EXCLUSIVE — Mahavir Tower, Ahmedabad SNAP — Dr. Yagnik Road, Rajkot CORALS — Shahupuri, Kolhapur KOHINOOR CLOTH STORES — M.G Road, Ahmednagar · INTERNATIONAL COLLECTIONS — Ichalkaranji

SOUTH ZONE

AGENCY OLYMPIA — Near Tourist Hotel, Panaji BINGO — Abid Road, Hyderabad SELECTIONS — Abid Road Hyderabad, CITIZEN COLLECTIONS — Basheerbagh, Hyderabad CHARMS — Koti, Hyderabad CASH — Swapna Lok, Secunderabad YAX & YAX — Labbipet, Vijaywada AMIGO — Brigade Road Bangalore MENS FAVOURITE SHOP — M.G Road & Commercial Street, Bangalore HANDSOME — Mangalore ASHIRWAD GARMENTS — Shimoga, Karnataka RED EYE — Cathedral Road, Madras KINGS COURT — Chamundi Complex, Salem

NORTH ZONE

TREND SETTERS — Sector 17 'C', Chandigarh THAKRAL & SONS — Model Town, Yamuna Nagar KHURANA & SONS — Main Bazar, Pathankot BIG BUS — Residency Road, Jammu SURI TRADERS — Pacca Danga, Jammu SINDHUR — Kalpetta DEETEES — Kalpetta DIWANCHAND ATMARAM — Simla LAMBA & LAMBA — 40, Janpath Market, Lucknow KAYSONS — 48, Hazaratganz, Lucknow JINGLE BELLS — Raja Park, Jaipur FASHION PALACE — Nai Sarak, Gwalior LIBAAS-E-HUNAR — Hardwar

DELHI

GIFT EMPORIUM — Green Park Extension SUPER GARMENTS — Kamla Nagar, FOUR SEASONS — Kamla Nagar CREATIONS — Lajpat Nagar COMARSONS — Karol Baugh, ZENITH — Karol Baugh GOGIA'S — Greater Kailash VINTAGE — Connaught Place, JAYDEE SONS — Connaught Place GALAXY COLLECTIONS — Ashok Vihar LUNGANIS — South Extn. Part I

BOMBAY

BULCHAND'S EMPORIUM, GRAND BAZAR — Colaba Causeway VINOD APPARELS — Kalaghoda FLORA'S MENS WEAR — Fountain, R. BAGOOMAL — Fountain DAVYSONS — Fountain VASHANI CLOTH STORES — Fort ASIATIC DEPARTMENTAL STORES — Churchgate ROOPAM — Crawford Market SAGAR MENS WEAR — Kalbadevi Road TAKE OFF — Kalbadevi Road PATLOON — Charni Road, POSHAQUE — V.P. Road SEQUEIRA COLLECTIONS — Tardeo ROOPALI — Kemps Corner VISHAL BOUTIQUE — Heera Panna, Haji Ali KANTI STORES — Dadar (W) MEHTA'S COLLECTION — Dadar T.T. SHIVOM — Sion Circle TELON, PARISONS, GIMMICKS, STERLING FASHIONS, CHOICE CENTRE — Hill Road, Bandra CITY BOY FASHIONS — Turner Road, Bandra ANEES — Linking Road, Bandra MAYURA BOUTIQUE — Khar (W) SIXER — Santacruz (W), GREEN BELL — Juhu, Vile Parle (W) SHIRT 'N' SLACKS — Vile Parle (E) JEMSONS — Irla, Vile Parle (W) CITY FASHIONS — Andheri (E) SAHEEB — Borivali (W) AKBARALLY'S — Chembur MY SHOPPEE — Mulund IMPRESSION — Mulund LAIZER — Thane LEO COLLECTIONS — Thane.

MANZ
PANTALOON
Ready-to-wear Trousers
Admn. & Sales Office
Manz Wear Pvt. Ltd.
G-11, Marol Industrial Area,
M.I.D.C. Marol, Andheri (East),
Bombay 400 093.
Ph: 6345006/6348483

देश

१६ फरवरी : बोडोलैंड आंदोलन ने गति पकड़ी, १२० घंटे के असम बंद का आह्वान, सेना सतर्क। ५७ वर्षीय एसके सिंह भारत के नये विदेश सचिव नियुक्त।

१७ फरवरी : शिवसेना के महासचिव यशपाल देवरस की आतंकवादियों द्वारा हत्या। श्रीनगर में रुश्दी की किताब के विरोध में हिंसा।

१८ फरवरी : पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां तेज, राकेट द्वारा पुलिस थाने पर हमला। राजीव गांधी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के मसले को शीघ्र हल करने की घोषणा।

१९ फरवरी : श्रीमती गांधी के विश्वासपात्र सहयोगी आरके धवन की मंत्रिपरिषद सचिवालय में विशेष कार्यस्थ अधिकारी पद पर वापसी, अनेक सचिवों के पदों में फेरबदल। श्रीमती सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार, नूरुल हसन उड़ीसा, टीवी राजेश्वर पश्चिम बंगाल तथा एसके भटनागर सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त।

२० फरवरी : रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को शीघ्र सुलझाने हेतु फैजाबाद में अधर में फंसे मुकदमों की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा २३ फरवरी को सुनवाई के निर्देश।

२१ फरवरी : राष्ट्रपति आर वेंकटरमण द्वारा धर्म को राजनीति से अलग रखने का आह्वान। जमशेदपुर में दो गुटों में संघर्ष, कर्फ्यू लागू।

२२ फरवरी : सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा फेयरफैक्स मसले की पुन: जांच का आग्रह। नरेश चंद्र नये रक्षासचिव नियुक्त। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भोपाल गैस कांड से संबंधित समझौते की भर्त्सना।

२३ फरवरी : रेल राज्य मंत्री माधव राव सिंधिया द्वारा ८९-९० का रेलवे बजट लोकसभा में पेश, माल भाड़े में बढ़ोतरी।

२४ फरवरी : बहुराष्ट्रीय यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किये गये मुआवजे का भुगतान। कानपुर कपड़ा मिलों के कर्मचारियों द्वारा तीसरे दिन भी रेल जाम। रुश्दी की किताब को लेकर बंबई में दंगा, १० मृत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नवजोत सिद्धू को वेस्टइंडीज दौरे पर जाने की अनुमति।

२५ फरवरी : बंबई के गिरगौम न्यायालय द्वारा हाजी मस्तान रिहा, किंतु ७ दिनों तक बंबई से बाहर रहने का आदेश।

२६ फरवरी : डा० हेडगेवार जन्मशताब्दी समारोह मनाने हेतु लखनऊ में हिंदू संगम, सरकारी नीतियों की भर्त्सना।

२७ फरवरी : सरकार द्वारा विवादास्पद पांडेय अवार्ड वापस लेने पर १०७ घंटे का ऐतिहासिक रेल-रोको आंदोलन समाप्त। वधवा समिति का कार्यकाल न बढ़ने के विरोध में दिल्ली के वकीलों द्वारा हड़ताल। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विपक्ष संबंधी बयान का विपक्ष द्वारा व्यापक विरोध। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पेरेज डी कुइयार दिल्ली पहुंचे।

२८ फरवरी : वित्तमंत्री एसबी चह्वाण द्वारा विपक्ष की अनुपस्थिति में ८९-९० का ७, ३३७ करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश।

आरके धवन

कानपुर में १०७ घंटे का रेलजाम

रुश्दी

हिरोहितो

विदेश

१६ फरवरी : श्रीलंका संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल यूएनपी को पूर्ण बहुमत। पाकिस्तान तथा अन्य मुस्लिम देशों से मौत के दस्ते 'सेटेनिक वर्सेज' के लेखक सलमान रुश्दी की हत्या के लिए लंदन रवाना।

१७ फरवरी : ईरान ने ब्रिटेन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, ब्रिटिश सरकार से रुश्दी की पुस्तक प्रकाशित करने की सफाई मांगी।

१८ फरवरी : सलमान रुश्दी ने खेद व्यक्त किया, ईरान हत्या पर अटल। पाकिस्तान द्वारा एन्टीटैंक मिसाइल बनाने का राजफाश। ओपेक (पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन) ने तेल उत्पादन घटाया।

१९ फरवरी : अफगानिस्तान में आपातकाल लागू, भीषण संघर्ष में १६ विद्रोही मृत। बांग्लादेश में वामपंथी दलों के बीच संघर्ष।

२० फरवरी : अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबउल्ला द्वारा सेना परिषद का गठन। 'सेटेनिक वर्सेज' का उर्दू में अनुवाद कर रहे स्वीडिश निवासी को हत्या की धमकी। ब्रिटिश सरकार ने ईरान की धमकियों से निबटने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) से सहयोग मांगा।

२१ फरवरी : ईरान ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों से अपने दूत वापस बुलाये। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों द्वारा यूएनपी पर चुनावों में धांधली का आरोप।

२२ फरवरी : अमरीकी कांग्रेस में जोधपुर के कैदियों की रिहाई संबंधित भारतीय व्यापार विरोधी बिल पेश। सुलतान अली किश्तमंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त।

२३ फरवरी : न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन के दबाव में आकर ईरान का विरोध किया। पाकिस्तान द्वारा तुर्की को मिसाइल तकनीक देने की पेशकश। जापान के स्वर्गीय सम्राट हिरोहितो के अंतिम संस्कार हेतु १६० देशों के प्रतिनिधि जापान पहुंचे।

२४ फरवरी : अमरीकी सुपर आणविक प्रोजेक्ट में भारत द्वारा ५ करोड़ डालर की सहायता की घोषणा। पाक द्वारा चीन की मदद से 'अन्जा' मिसाइल का निर्माण।

२५ फरवरी : अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश पूर्वी-पश्चिमी संबंधों को दृढ़ करने हेतु बीजिंग पहुंचे। ब्रिटिश गृहसचिव डगलस द्वारा ब्रिटेन के मुस्लिमों को शांत रहने की चेतावनी।

२६ फरवरी : अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश और चीन के नेता झेंगझियाओ पिंग के बीच वार्ता, अमरीका द्वारा कंपूचिया के नेता राजकुमार नरोतम सिहनुक की सहायता की घोषणा। सोवियत संघ के विदेश मंत्री एडुअर्ड शेवर्दनाटजे ईरान पहुंचे, खुमैनी से लंबी बातचीत। ईरानी मजलिस (संसद) द्वारा ब्रिटेन से राजनयिक संबंध तोडने का बिल पारित।

२७ फरवरी : अफगान विद्रोहियों द्वारा जलालाबाद पर बम वर्षा, सैकड़ों मृत। ४० घंटे की चीन राजनयिकों से बातचीत के बाद जार्ज बुश स्वदेश वापस। ओलंपिक की स्वर्णपदक विजेता जैकी जायनर कर्सी की ट्राफियों सहित कार चोरी।

२८ फरवरी : बांग्लादेश के उपप्रधानमंत्री प्रोफेसर एमए मतीन द्वारा रुश्दी पर मुकदमा चलाये जाने का आग्रह।

अनोखा प्रेम विवाह

शादी के समय और शादी के बाद : मनीष और मधुबाला

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

इतिहास में ऐसी अनगिनत मिसालें हैं जिनके आधार पर प्रेम संबंधों को धर्म, जाति, आयु और परिस्थितियों की हद से मुक्त माना जाता है। सचाई तो यह है कि आज भी असली जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जहां लड़के-लड़कियां मां-बाप की परवाह किये बिना, समाज के बंधनों को तोड़कर या तो शादी के बंधन में बंध जाते हैं या अपने आपको प्रेम की वेदी पर न्यौछावर कर देते हैं। किंतु ऐसी मिसालें कम मिलती हैं जहां समलिंगी प्रेमी प्रकृति को चुनौती देकर एक साथ रहने के उद्देश्य से विवाह करते हों। हाल में दिल्ली के पहाड़गंज मोहल्ले की मधुबाला ने अपनी सहेली मंजु चावला से विवाह करके प्रेम संबंधों के इतिहास में शायद एक नया अध्याय जोड़ा है। इन दोनों सहेलियों में ऐसी घनिष्ठता थी कि सदा साथ रहने के उद्देश्य से मंजु ने लिंग परिवर्तन कराने का जोखिम भी उठाया और मंजु चावला से मनीष चावला बन गयी।

हुआ यों कि सात वर्ष पहले जब १७ वर्षीय मंजु राजौरी गार्डेन इलाके में अपनी चाची के घर गयी थी, तब उसकी मुलाकात मधुबाला से हुई थी। इत्तफाक से मधु की उम्र भी लगभग १७ वर्ष ही थी। चूंकि दोनों का स्वभाव काफी मिलता-जुलता था, इसलिए पहली मुलाकात में ही दोनों सहेली बन गयीं। फिर अक्सर दोनों मिलती रहीं। धीरे-धीरे घनिष्ठता ऐसी बढ़ी कि दोनों ने हरदम साथ रहने का सपना देखना शुरू कर दिया।

पिछले साल मधु के पिता रामचंद्र सिंह ने जब मधु की शादी के लिए वर खोजना शुरू किया, तो मधु के जरिये यह खबर मंजु तक पहुंची। जाहिर है, जो सहेलियां आपस में हरदम साथ रहने की इच्छा रखती हों, उनके लिए शादी की खबर अच्छी कैसे हो सकती थी? बस फिर क्या था? मधु ने अपने परिवारवालों को भनक दिये बिना मंजु से विवाह करने की ठान ली और मंजु ने लिंग-परिवर्तन की योजना बना डाली।

एक दिन मधु को बताये बिना ही अपने मां-बाप की अनुमति लेकर मंजु करोल बाग स्थित बाली नर्सिंग होम में भरती हो गयी जहां १४ जनवरी, १९८९ को उसका आपरेशन हुआ। मधु जब मंजु से मिलने के लिए नर्सिंग होम पहुंची, तभी उसे इस आपरेशन के बारे में पता चला। इस संबंध में मधु कहती है, "मंजु १३ जनवरी को भी मेरे यहां आयी थी, लेकिन उसने आपरेशन के संबंध में मुझे बताया नहीं। लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंची, तो सबने मुझे बताया कि मुझसे शादी करने के लिए मंजु ने लिंग परिवर्तन कराया है, जिसमें उसे काफी तकलीफ झेलनी पड़ी है।" मंजु के निर्णय ने ही मधु को शादी के लिए मन से तैयार होने पर मजबूर किया।

मंदिर में शादी : दूसरी तरफ मधु के पिता रामचंद्र सिंह ने फरवरी के पहले हफ्ते में १० फरवरी को मधु की शादी की तारीख तय कर दी थी। मधु को जैसे ही १० फरवरी को शादी होने की खबर मिली, वह सीधे मंजु के घर पहुंच गयी जो कुछ दिन पहले मंजु से मनीष बन गयी थी। दोनों ने तुरंत शादी कर लेने का फैसला किया और अदालत पहुंच गये। इस संबंध में मनीष बताता है, "अदालत में शादी के इतने फार्म थे कि सबको १२ बजे तक भरा नहीं जा सकता था। इसलिए हम दोनों घर वापस आये और पास के मंदिर में गये जहां चार बजे शाम को हमने वैदिक ढंग से शादी कर ली। मेरे मां-बाप के अलावा २५ और परिचित लोग तथा दोस्त शादी के समय मौजूद थे।" इस शादी में मधु के पिता को आमंत्रित नहीं किया गया था।

१५ फरवरी को मधु के पिता रामचंद्र सिंह ने राजौरी गार्डन थाने में धारा ३६६ के तहत रपट लिखायी कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। रिपोर्ट में लिखाया गया था कि मधु का अपहरण मनीष चावला से शादी के लिए कराया गया था। अगले दिन पुलिस ने मधु और मनीष को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रात भर थाने में रखा।

अगले दिन मधु को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कुमारी आशा मेनन के सामने पेश किया गया। मधु से मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान देने को कहा गया, तो उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह मनीष के साथ जाना चाहती है।

जब अदालत को सचाई का पता चला, तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पूर्व ही मधु को छोड़ दिया। हारकर मधु के परिवार के लोग बैठ गये।

मधुबाला और मनीष विवाह करके और सभी मोर्चों पर सफल होते हुए खुशहाल जिंदगी तो गुजार रहे हैं, किंतु मनीष को आज भी इस बात का दुख है कि मधु के मां-बाप अब भी उनके विवाह को स्वीकार क्यों नहीं करते? हालांकि मधु इस विषय पर अपना दोटूक नजरिया पेश करती है कि सब धीरे-धीरे ठीक हो जायेगा, आखिर उन्होंने जन्म दिया है, तो कब तक नजरें फेरे रहेंगे?

—अभय अग्रवाल

आओ मिलकर हम 'घर-घर' खेलें!

Practical guide to
home landscaping
IKEA 1987

जब जीवन भर की पूंजी लगायेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिये अपनी निशानी भी तो छोड़ कर जायेंगे।

जी हां! आखिर जीवन भर की पूंजी लगाकर जब अपना घर बनायेंगे तो किसी भी चीज़ में समझौते का सवाल ही नहीं उठता। खासकर सीमेन्ट का चुनाव तो बहुत ही सोच समझकर कीजियेगा।

फिर सबसे बेहतर सीमेन्ट की सही पहचान तो किसी अच्छे बिल्डर को ही हो सकती है, है ना? तो भारत के नं. 1 बिल्डर जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के वर्षों के अनुभव का फायदा अब आप भी उठाइये। जिस सीमेन्ट से वे बड़े-बड़े पुल और बांध देश-विदेश में बनाते हैं, उसी भरोसेमन्द सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट से आप भी अपना घर बनवाइये।

सीमेन्ट की क्वालिटी का मापदण्ड हमेशा उसमें उपयोग किये गये चूना-पत्थर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इसीलिये सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट का कारखाना देश के सबसे बेहतरीन चूना-पत्थर की खदानों में पास स्थित है। साथ ही साथ सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट अत्याधुनिक कम्प्यूटर युक्त तकनीक से बनाया जाता है।

तभी तो सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट में है बेजोड़ पकड़, लाजवाब मजबूती और बेमिसाल भरोसा।

जब भारत के नं. 1 बिल्डर के अनुभवों से बना सीमेन्ट उपलब्ध है, तो फिर भला किसी और सीमेन्ट को क्यों खरीदें?

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट : इसे नाम से मांगिये।

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट की गारंटी
- तुरन्त मज़बूत पकड़
- 28 दिनों के बदले सिर्फ 3 दिनों में 330 kg/cm² की कम्प्रेसिव मज़बूती।
- हर बोरी में पूरा वज़न – पूरे 50 किलो।

GUARANTEED QUALITY

मजबूत रहे यह बंधन-जीवनभर

सुपरप्लस
जेपी
सीमेन्ट

मास्टर बिल्डर

जयप्रकाश इन्डस्ट्रीज़ का एक उत्कृष्ट उत्पादन

LINTAS (DELHI) JI 58 2821 H

टीपू सुल्तान का दुर्भाग्य

बेशक वह इतिहास का महत्वपूर्ण नक्षत्र है, लेकिन हर कहीं बदकिस्मती का मारा है। चूंकि उसके किस्से प्रायः उसके शत्रु अंग्रेजों द्वारा और उनके बनाये हिंदुस्तानी इतिहासकारों द्वारा ही लिखे गये, इसलिए जीवन में अच्छा होकर भी इतिहास में वह बदनाम ही रहा। संस्कृतिकर्मियों ने उसकी शख्सीयत अवश्य पहचानी और उसे उसके दृश्य-श्रव्य आयामों के साथ समाज के सामने पेश करने की कोशिश भी की। लेकिन उसके दुर्भाग्य ने इन संस्कृतिकर्मियों को भी आ घेरा और एक से बढ़कर एक हादसा होता चला गया। क्या कोई अंत है इस दुर्भाग्य का?

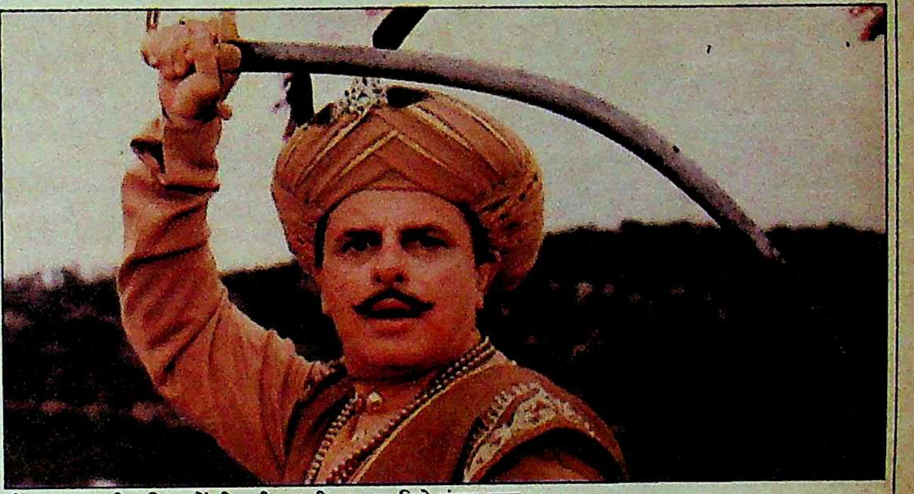

टीपू सुल्तान की भूमिका में टीपू की असली तलवार लिये संजय खान

टीपू सुल्तान पर भव्य फिल्में बनाने की योजना कई बड़े-छोटे निर्माताओं ने बनायीं, लेकिन किसी-न-किसी कारण उनकी योजना खटाई में पड़ गयी। 'सन आफ इंडिया' के बाद स्व० महबूब खान, दिलीप कुमार को टीपू की भूमिका में लेकर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन हृदय गति रुक जाने के कारण उनका 'प्रोजेक्ट' ठप पड़ गया। टीपू के बचपन की भूमिका के लिए उन्होंने मास्टर साजिद को चुना था। स्व० सोहराब मोदी ने भी 'झांसी की रानी' के बाद टीपू सुल्तान पर फिल्म बनाने की योजना बनायी, लेकिन 'झांसी की रानी' की भारी असफलता के बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गयी कि कोई भी 'फायनेंसर' आगे आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके पहले प्रख्यात अभिनेता श्याम एक फिल्म निर्माता की फिल्म में टीपू की भूमिका करनेवाले थे, लेकिन फिल्म 'शबिस्तान' में घोड़े से गिरकर उनकी मौत हो जाने के कारण वह योजना भी वहीं-की-वहीं रह गयी। के आसिफ 'महाभारत' तथा 'हैदरअली और उसका बेटा टीपू' (पृथ्वी राज कपूर तथा राजेंद्र कुमार) बनाना चाहते थे, लेकिन 'सस्ता खून महंगा पानी' के निर्माण के दौरान राजेंद्र कुमार के सिताराना व्यवहार से वे इतने क्षुब्ध हुए कि टीपू से संबंधित फिल्म की योजना न केवल वहीं रोक दी, बल्कि अधूरी बनीं 'सस्ता खून महंगा पानी' का निर्माण भी रद्द कर दिया। इसके अलावा और भी कई निर्माताओं ने इस 'प्रोजेक्ट' पर पानी की तरह रुपए बहाकर इसे फाइल में बंद कर दिया। अनुमानतः टीपू सुल्तान पर फिल्म की फाइलबंद योजनाओं पर एक करोड़ रु० बर्बाद हुए, लेकिन टीपू सुल्तान सिनेमा हाल के परदे तक नहीं पहुंच सके।

एक और अग्निकांड : सारे किस्से जानते हुए इस कठिन कार्य का बीड़ा उठानेवाले संजय खान ने पहले 'टीपू सुल्तान' के संगीत की जिम्मेदारी नौशाद को सौंपी थी। अगर श्याम (दिल्लगी), महबूब, के आसिफ तथा सोहराब मोदी ने टीपू सुल्तान पर फिल्में बनायी होतीं, तो भी संगीत निर्देशन नौशाद का ही होता। इत्तिफाक से मैसूर जैसा हादसा नौशाद की जिंदगी में भी एक बार हुआ था जब उनके समेत सभी मौत के मुंह में पहुंच कर निकल आये थे। नौशाद ने 'माया' को बतलाया, "हम लोग एक फिल्म के लिए अस्तबल की शूटिंग एक स्टूडियो में कर रहे थे, जिसके लिए बढ़िया नस्ल के अरबी घोड़े मंगवाये गये थे। स्टूडियो का दरबान सेट का दरवाजा बाहर से बंद कर खाना खाने चला गया और हम लोग भीतर शूटिंग करते रहे। अचानक आग की चिंगारी से घोड़े बिदक गये और स्टूडियो के भीतर बेतहाशा लोगों को रौंदते-फांदते तूफान मचाने लगे। हीरोइन से लेकर हर कोई चीखने-चिल्लाने तथा जिसे जहां जगह मिलती छिपने की कोशिश करने लगा। रिकार्डिंग रूम में बैठा साउंड रिकार्डिस्ट इस उछल-कूद, हंगामे तथा चीख-चिल्लाहट को शूटिंग का सीन समझ कर खुश होता रहा कि बहुत अच्छा 'इफेक्ट' कलाकार दे रहे हैं। आराम से भोजन कर दरबान ने आकर जब गेट खोला, तो एक-एक कर सभी घोड़े सेट से बाहर की ओर आंधी की तरह भागे। हतप्रभ दरबान जब सेट पर पहुंचा, तो लोगों की चीख-चिल्लाहट जारी थी। हीरोइन, कई दूसरी अभिनेत्रियां तथा कलाकार बेहोश पड़े थे और साउंड रिकार्डिस्ट की माइक पर आवाज गूंज रही थी, "गुड शॉट! मारवेलस शॉट!"

ज्योतिषी की चेतावनी : पिछले वर्ष जब संजय खान ने, टीपू सुल्तान के पहले, अपनी बहुसितारीय फिल्म 'सरजमीं' का कई लाख रु० खर्च कर होटल सेंटोर में भव्य मुहूर्त किया था, तब ईश्वरीय बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के पुरोहितों को आमंत्रित किया था। मुहूर्त-शॉट के समय वे सभी अपने-अपने धर्मग्रंथों से पाठ कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने ज्योतिषी सुखलाल ठक्कर ने तब कहा था, "संजय खान विषम तथा अशुभ ग्रहों की स्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए वे जो भी काम शुरू करेंगे, वह बीच में ही रुक जायेगा, उन्हें अपयश का भी भागी बनना पड़ेगा, किसी हादसे का शिकार भी होना पड़ सकता है।" यही हुआ भी। 'सरजमीं' बड़े सितारों की भीड़ के बाद शूटिंग का मुंह नहीं देख सकी और 'टीपू सुल्तान' एक सप्ताह की शूटिंग के बाद ही दिल दहला देनेवाले हादसे का शिकार हो गया।

बात यहीं तक सीमित रहती, तो कोई बात न थी, पर मुद्रा कम्युनिकेशंस प्रा०लि० ने संजय खान तथा उनकी निर्माता संस्था के विरुद्ध बंबई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कुरुडकर की अदालत में एक करोड़ ३२ लाख, २० हजार रु० के हर्जाने का दावा ठोंक दिया है। 'टीपू सुल्तान' के प्रायोजक के रूप में पहले मुद्रा कम्युनिकेशंस से अनुबंध हुआ था। लेकिन संजय खान के एक प्रतिनिधि ने 'माया' को बतलाया, "मुद्रा कम्युनिकेशंस ने अनुबंध के अनुसार जब भुगतान नहीं किया, तो हमने अनुबंध रद्द कर दिया।" इसके बाद हिंदुस्तान थांपसंस (एचटीए) से अनुबंध हुआ। लेकिन वह भी सफल नहीं हुआ। इस समय एवरेस्ट विज्ञापन एजेंसी से इसके प्रायोजन का अनुबंध हुआ है।

असली मुद्दा : सवाल उठता है, क्या 'टीपू सुल्तान' सीरियल बन पायेगा? संजय खान को ठीक होने में कम-से-कम दो महीने लगेंगे। उनकी यूनिट के पांच सहायक निर्देशक, जिन्हें एक-एक

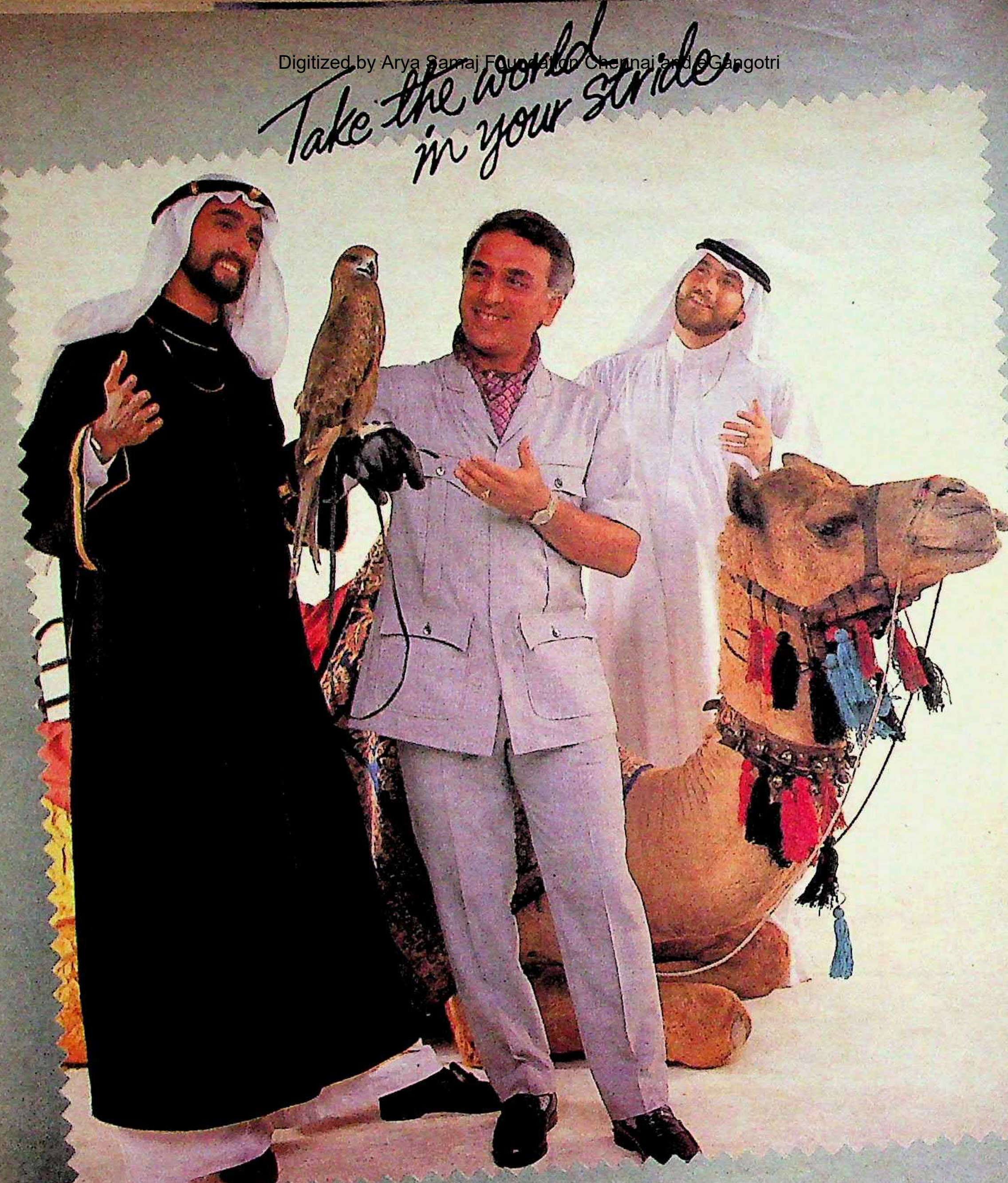
Take the world in your stride.

everest/86/SDM/264/M (2)

dinesh

Exclusives ▲ Suitings ▲ Co-ordinates ▲ Safaris

The choice of leading fashion houses, internationally.

Authorised dealers: **DARBHANGA:** Navin Vastralaya • **GAYA:** Dalmia Bros • Rajesh Stores • Swadeshi Vastralaya • Variety • **JAMSHEDPUR:** Diamond • Doongarsidas Biharilal • Paradise Fabrics • Textiles Centre • **TATANAGAR:** S M Thakkar.

आग की कथा, बचे की व्यथा

"वह एक गांव का एक घर था—नहीं, एक गांव के एक घर का नजारा। खजूर के पेड़ों और घास-पुआल से ही देहात की सूरत और माहौल रचा गया था। जिस स्टूडियो में यह सेट जमाया गया था, उसमें दो दरवाजे थे। एक इस सेट के कारण ही अवरुद्ध हो गया था, और दूसरा इसलिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि शूटिंग चल रही थी।

मंगलवार (७ फरवरी) को बाहर से शूटिंग की गयी और तय किया गया कि अंदर से बुधवार को शूटिंग की जायेगी। उस दिन सवेरे ८.०० से रात के ९.०० बजे तक शूटिंग चलती रही। इसके बाद निर्देशक संजय खान ने काम रोक दिया और कहा, "बारात की शूटिंग कल (गुरुवार, ९ फरवरी को) होगी।" लेकिन कुछ तकनीशियनों ने जब जोर देकर कहा कि वे रात में और काम करने को तैयार हैं, तब संजय खान के कहने से यूनिट ने शूटिंग का काम फिर चालू कर दिया।

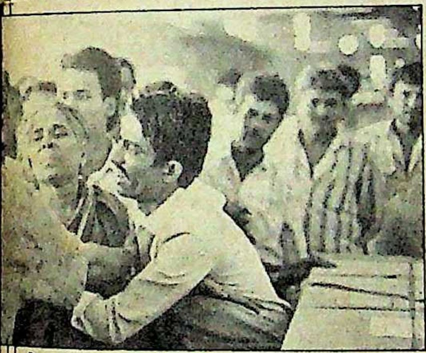
शोक-संतप्त एक परिवार

लपटदार पटाखेबाजी की पहली शूटिंग के समय कोई कलाकार पास में नहीं था। दूसरी बार ८ कनिष्ठ कलाकारों और ६ सहायकों को 'गुलदस्ते' (फ्लावरपॉट) के चारों ओर रहना था। कुछ लोगों की राय थी कि गुलदस्ते की आतिशबाजी की शूटिंग अंदर न की जाये। किंतु प्रोडक्शन (निर्माण) के कर्ताधर्ताओं ने इस राय पर ध्यान नहीं दिया और शूटिंग जारी रखी। मैं 'लाइट' तक जाने वाले तंग रास्ते पर जमीन से १५ फुट ऊपर था। 'फ्लावर पॉट' में आग लगायी गयी। उसकी लहर ऊपर उठी और देखते-देखते छत तक पहुंच गयी जहां आवाज 'डैंप' करने के लिए जूट, नारियल की जटा और टाट के बोरों का अंबार रखा था। बस, इस मामूली कारण से ही इस अंबार में आग लग गयी।

'पानी! ...पानी लाओ, आग बुझाओ! फौरन चिल्ला पड़े संजय खान। घबराकर मैं तंग रास्ते से नीचे कूद पड़ा, दौड़कर उधर गया जहां आग लगी थी, (सेट से) अवरुद्ध दरवाजे को धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। भीतर मेरा दोस्त महादेव आग से जूझ रहा था (जो बाद में मर गया)।...मैं उस बड़े दरवाजे के पास नहीं जा सका जो बाहर से बंद था। लेकिन मैंने यह साफ-साफ देखा कि तकरीबन पच्चीस आदमी लपटों में से चीखते-चिल्लाते निकल रहे हैं। वे फर्श पर तड़प रहे थे और मदद तथा पानी मांग रहे थे। उनमें से एक को मैंने जलते कपड़ों से अलग किया और थोड़ा पानी भी लाकर दिया। फिर मैंने देखा कि कुछ और लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो पहले ही बचकर बाहर निकल आये थे। ऐसों में प्रथम थे संजय खान जो भागे-भागे पास में ही खड़ी एक कार में जा बैठे और उसे खुद हांकते हुए अन्यत्र चले गये। तब तक समूची स्टूडियो आग में धहधह जलने लगी थी और उसके अंदर कोई आदमी बच जाये, यह कतई नामुमकिन था।"

यह बयान है 'लाइट ब्वाय' कुमार का जो ८ फरवरी को मैसूर की एक फिल्म स्टूडियो में, टीपू सुल्तान पर बन रही संजय खान की टीवी फिल्म की शूटिंग के दौरान, भीषण अगलगी का भुक्तभोगी साक्षी है। संजय खान की यूनिट ने 'प्रीमियर स्टूडियो' में कुल सात 'लाइट ब्वाय' लगाये थे। इनमें से कुमार बच निकला। लेकिन बाकी? ...कुमार के सामने जब यह प्रश्न रखा जाता है, तो उसकी आंखों में चटख-चटख कर, धधक-धधक कर जलती स्टूडियो और आग की लपटों में तड़पते उसके हमदम, हमसफर दोस्तों का नजारा उभर आता है। सचमुच, ऐसे हादसे से गुजरने के बाद अपने साथियों के बारे में कुछ कहना कितना मुश्किल होता है!

फिल्म जगत की अपूर्व दुर्घटना में महत्वपूर्ण कलाकारों और फिल्मकर्मियों सहित ४९ लोगों की जानें गयीं। ख्यातनामा निर्देशक करेकर, सौ फिल्मों के डिजाइनर तथा नामी ध्वनि अभियंता (साउंड इंजीनियर) अल्लाउद्दीन कुरेशी तथा कमाल पाशा, उदीयमान कलाकार—निर्देशक धीरज और मशहूर कैमरामैन असलम शैख जलकर कोयला बन गये। कुमार के अनुसार हीरोइन नीना गुप्ता, हैदरअली की भूमिका निभा रहे मुकेश खन्ना और युवक टीपू सुल्तान बने केवल शाह (जो टीवी श्रृंखला 'महाभारत' में कृष्ण भी बने थे) वेशविन्यास के लिए स्टूडियो से बाहर निकल आये थे, इसलिए बच गये, वरना ये प्रतिभाएं भी खाक हो गयी होतीं।

—जानकी दास

शॉट की बारीकी से जानकारी थी, तथा यूनिट के कई प्रमुख व्यक्ति कालकवलित हो चुके हैं। नयी यूनिट तैयार करने में उन्हें महीनों लगेंगे। नये सिरे से कास्ट्यूम तथा सेट बनवाने पड़ेंगे, जिनमें लाखों रु० का ऊपर से खर्च आयेगा। शूट की हुई कितनी फिल्म सुरक्षित है, अभी इसका पता नहीं। अभी तक एक एपीसोड पर छह लाख रु० खर्च का अनुमान था। अब अगर 'टीपू सुल्तान' बना, तो इसकी लागत ५ करोड़ रु० तक पहुंच जायेगी। स्वस्थ होने के बाद उन्हें हादसे से मृत तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की भारी राशि का इंतजाम करना पड़ेगा, मैसूर तथा बंबई में उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमों की कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर उन्होंने मुआवजा देने में कोताही की, तो फिल्म वर्कर्स एसोसियेशन उन्हें अदालत के कठघरे तक ले जाने के लिए तैयार है। फिल्म इंडस्ट्री में अधिकांश लोगों से, उनके अड़ियल स्वभाव के कारण, उनके संबंध खराब रहे हैं, इसीलिए उनकी मदद के लिए न तो इस समय इंडस्ट्री के प्रभावशाली लोग आगे आये और न ही बाद में उनके आगे आने की संभावना है। इसके अलावा मैसूर तथा बंबई के अस्पतालों में भर्ती उनकी यूनिट के लोग इसलिए भी क्रुद्ध हैं कि उन्हें वहां असहाय छोड़ कर सिर्फ उन्हें लेकर उनके परिवार के लोग बंबई चले आये और उनकी चिकित्सा की भी कोई व्यवस्था नहीं की। अभिनेता राममोहन तथा फिल्म वर्कर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि बालकिशन देसाई मैसूर जाकर शौकत शेख को बंबई ले आये और जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया।

एक फिल्मकार ने 'माया' को बतलाया, "किस बात की सहानुभूति? उन्होंने कर्नाटक सरकार की मदद पाने के लिए वहां आर्कियोलाजी विभाग को कीमती कंप्यूटर सेट उपहार में दिया, टीपू सुल्तान रिसर्च सेंटर को दो लाख रु० दिये, लेकिन मुफलिसी में दिन बिता रहे टीपू सुल्तान के वंशजों की सहायता की बात भी उनके जेहन में नहीं आयी।" संजय खान के विरुद्ध यह विवाद इस कदर बढ़ गया है कि लोग यह मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि वे सचमुच ६०-६५ प्रतिशत जले हुए हैं। लेकिन संजय खान की पत्नी जरीना खान इन सबसे घबड़ातीं नहीं—"हम सिर्फ इसलिए अब्बास (संजय का असली नाम) से लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं कि इससे उन्हें मानसिक तथा शारीरिक तकलीफ होगी और उन्हें ठीक होने में ज्यादा समय लग जायेगा। अब्बास ठीक होते ही 'टीपू सुल्तान' का निर्माण पूरा करेंगे, आखिर यह उनकी जिंदगी का सपना है। वे बहुत ही भावुक हैं, उन्हें असली हादसे तथा मृतकों (४९) की सही संख्या के बारे में बतलाया नहीं गया है। हम इस बात पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं कि अपने किसी भी साथी और उसके परिवार को तकलीफ नहीं होने देंगे।"

—रवींद्र श्रीवास्तव

टीपू सुल्तान

इतिहास से स्टूडियो तक

टीपू सुल्तान सीरियल का एक दृश्य

१९२३ में कराची में पैदा भगवान गिडवानी अपने परिवार के साथ, विभाजन के बाद, बंबई आ गये थे। बंबई विश्वविद्यालय से बीए तथा एलएलबी परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गये और नागरिक उड्डयन तथा कानूनी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की। हेग स्थित विश्व अदालत में वे भारत के वकील, फिर १९७६-७८ में भारतीय नागरिक उड्डयन के महानिदेशक भी रहे। टीपू सुल्तान के इतिहास से प्रभावित हो उन्होंने ११ वर्षों तक देश-विदेश में टीपू सुल्तान के बारे में शोधकार्य करने के बाद 'द सोर्ड आफ टीपू सुल्तान' लिखा जिसकी एक प्रति संजय खान ने दिल्ली हवाई अड्डे पर खरीदी और बंबई तक के सफर में पूरी पुस्तक पढ़ डाली।

"टीपू सुल्तान की शख्सीयत से मैं तब प्रभावित हुआ था जब स्कूल के एक टूर के साथ श्रीरंगपट्टम गया था और वहां पर गाइड को टीपू सुल्तान की विशेषताएं बतलाते हुए पाया था।" संजय खान ने 'माया' को हादसे से तीन दिन पहले ५ फरवरी '८९ को महालक्ष्मी रेसकोर्स मैकडावेल इंडियन डर्बी घुड़दौड़ के समय, बतलाया था। उनका कहना था, "इतिहास में टीपू सुल्तान के बारे में जो कुछ हमें पढ़ाया जाता था, वह उस गाइड के बयान से एकदम भिन्न था। अंग्रेजों ने उसे धर्मांध, असहिष्णु, क्रूर तथा ब्राह्मणों की जनेऊ उतारनेवाला बतलाया था, जबकि बाद में मुझे पता चला कि टीपू की फौज के २४ जनरलों में १२ मुसलमान तथा १२ हिंदू थे। उसके दरबार तथा फौज में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे टीपू के लिए हर क्षण जान देने के लिए तैयार रहते थे। बस, तभी से टीपू मेरा आदर्श बन गये। मैंने जब से भगवान गिडवानी की पुस्तक पढ़ी, तभी से मेरे मन में इस पर फिल्म बनाने का भूत सवार हो गया।"

१९७८-७९ में संजय खान ने 'चांदी-सोना' फिल्म पूरी करने के बाद ४ करोड़ रु० की लागत से 'टीपू सुल्तान' बनाने की योजना बनायी, पूरी तैयारियां कीं। लेकिन कोई भी वितरक जब फिल्म को हाथ लगाने के लिए आगे नहीं आया, तो उन्हें दोस्तों की सलाह पर फिल्म योजना वहीं रोक देनी पड़ी। उस समय बहुसितारीय तथा महंगी-से-महंगी फिल्में एक करोड़ रु० की लागत ('शोले' : सवा करोड़ रु०) में बन जाती थीं।

"टीवी सीरियलों का जमाना आने पर मैं फिर उत्साहित हुआ," संजय खान आगे बताते हैं, "भगवान गिडवानी ने भी सीरियल के लिए 'अप्लाई' (आवेदन) कर रखा था, लेकिन किन्हीं मुद्दों के तहत उन्हें मंडी हाउस से इजाजत नहीं मिल पा रही थी। गिडवानी से बात कर मैंने नये सिरे से 'अप्लाई' किया, दो वर्ष लग गये थे मंडी हाउस की मंजूरी मिलने में। मेरे पास कथा थी ही, अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। सीरियल की पटकथा और संवाद लिखे तथा २ अक्तूबर '८८ को 'टीपू सुल्तान' का मुहूर्त ललित पैलेस में कर दिया। कर्नाटक सरकार ने न केवल टीपू सुल्तान की असली कीमती तलवार शूटिंग के लिए देने की मंजूरी दे दी, बल्कि श्रीरंगपट्टम स्थित महल भी मुहूर्त के लिए खोल दिया।"

महल की दीवारों तथा दरवाजों पर सोने चांदी के पत्तर जड़े थे और वहां जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। संजय खान ने टीपू सुल्तान के काल के अनुसार २० लाख रु० से अधिक लागत के कास्ट्यूम सिलवाये तथा २५० से अधिक तलवारें बनवायीं जिनकी कीमत २०० रु० से ७०० रु० प्रति तलवार पड़ी। टीपू सुल्तान के असली महल को अंग्रेजों ने जला दिया था, अतएव उसके सेट तथा दूसरे सेट बनाने के लिए संजय खान ने मैसूर के प्रीमियर स्टूडियो को लंबे अरसे तक के लिए किराये पर ले लिया। इसी स्टूडियो में एक-डेढ़ दशक पहले मोहन कुमार ने अपनी एक फिल्म की शूटिंग की थी। वे उसे खरीदने पर भी विचार कर रहे थे। लेकिन फिल्म के पिट जाने तथा अचानक मन बदल जाने पर उन्होंने इस स्टूडियो को खरीदने का विचार त्याग दिया। संजय खान ने पूरी शूटिंग मैसूर, श्रीरंगपट्टम इलाके में ही करने की योजना बनायी थी।

सीरियल का २१वां एपीसोड (भाग) उन्होंने पायलट के रूप में फिल्माया था जिस पर लगभग १८ लाख रु० का खर्च आया था। पायलट में संजय खान के अलावा डा० श्रीराम लागू (वजीरे आजम), कंवलजीत (इकराम उल्लाह), बॉब क्रिस्टो (अंग्रेज अफसर मैथ्यूज), दिलीप ताहिल (मीर सादिक), सुरेंद्र पाल (अलीरजा), सत्येन कप्पू (गफ्फार) ने भाग लिया था। सिर्फ होटल में ठहरने तथा आने-जाने पर ही लगभग दो लाख रु० खर्च हुए थे। विश्व दूरदर्शन के इतिहास में अब तक तथा आनेवाले वर्षों में सबसे महंगा पायलट होने का रुतबा इसे मिलेगा, क्योंकि आम तौर पर एक पायलट की शूटिंग पर डेढ़ लाख रु० का ही खर्च आता है। इसके अलावा उन्होंने मुहूर्त के समय ही कर्नाटक आर्कियालाजी (पुरातत्व) विभाग को २ लाख रु० कीमत का कंप्यूटर प्रदान किया था तथा टीपू सुल्तान रिसर्च सेंटर को दो लाख रु० की आर्थिक सहायता भी दी थी।

संजय खान १६ एमएम तथा कुछ महत्वपूर्ण हिस्से ३५ एमएम में शूट कर रहे थे ताकि उसे ७० एमएम में डेवलप कर तीन-साढ़े तीन घंटे की फिल्म संपादित कर अलग से तैयार कर सकें तथा उसे दूसरे विदेशी भाषाओं में डब (परिवर्तित) कर सकें। इसके लिए उन्होंने फ्रेंच निर्माताओं से भी कांस फिल्मोत्सव के दौरान, सहयोग के लिए बात की थी। ५०-५० मिनट के ५२ एपीसोडोंवाले इस सीरियल के प्रसारण की तिथि मंडी हाउस ने शनिवार (२९ अप्रैल '८९) तय कर रखी थी। हादसे के पहले संजय खान सिर्फ पहला एपीसोड ही पूरा कर सके थे, उसमें भी कुछ काम बाकी ही था। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पायी है कि हादसे के दिन वे टीपू सुल्तान के दादा (अरुण पाल) तथा दादी (नीना गुप्ता) के निकाह का दृश्य तैयार कर रहे थे या टीपू सुल्तान के विवाह का। अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कहते हैं। ■

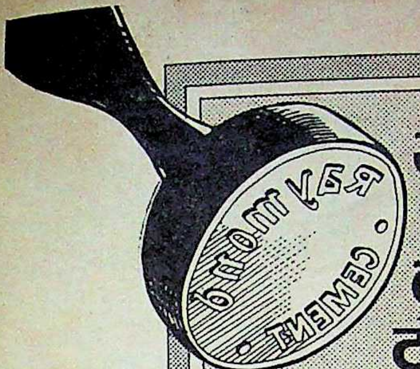

जब किसी निर्णय पर सालों-साल साथ निभाने की बात निर्भर हो तो ठोस प्रमाण उसमें मदद करते हैं

प्रमाण १ : गुणवत्ता
रेमण्ड का नाम ही सर्वोच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय है.

प्रमाण २ : मज़बूती
बी आइ एस के मानकों से निश्चय ही ज़्यादा 'कॉम्प्रेसिव' शक्ति.

प्रमाण ३ : ब्लेन
महीनतम ब्लेन के कारण अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मनचाही मज़बूती की गारंटी.

प्रमाण ४ : जमाव गुण
रेमण्ड सीमेंट पूर्ण जमाव का आश्वासन देता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव की अवधि बी आइ एस मानकों से बेहतर है.

प्रमाण ५ : विक्रेताओं का जाल
देशभर में रेमण्ड के अधिकृत विक्रेताओं का जाल शत प्रतिशत असली सीमेंट उपलब्ध कराता है.

प्रमाण ६ : पैकेजिंग
स्वचालित रोटरी पैकेजिंग मशीनों द्वारा सबसे मज़बूत प्लास्टिक और जूट की बोरियों में पैक याने निकाल लिए जाने का अंदेशा ही नहीं.

प्रमाण ७ : बचत
कोई अन्य सीमेंट हर बार इतने ठोस लाभों की गारंटी दे नहीं सकते.

प्रमाण ८ : हमारे कुछ ग्राहक
एन टी पी सी, ऑयल इंडिया लि., भारतीय रेलवेज़, वायजैक स्टील प्लांट, ईस्ट इंडिया होटल्स लि., आइ टी सी लिमिटेड, वोल्टास लि., टाटा रोबिन्स फ्रेसर, निटको टाइल्स, अंसल हाउसिंग प्रा. लि., एस.आर.एफ. निप्पॉन डेनरो इस्पात लि. जी.ई.सी.

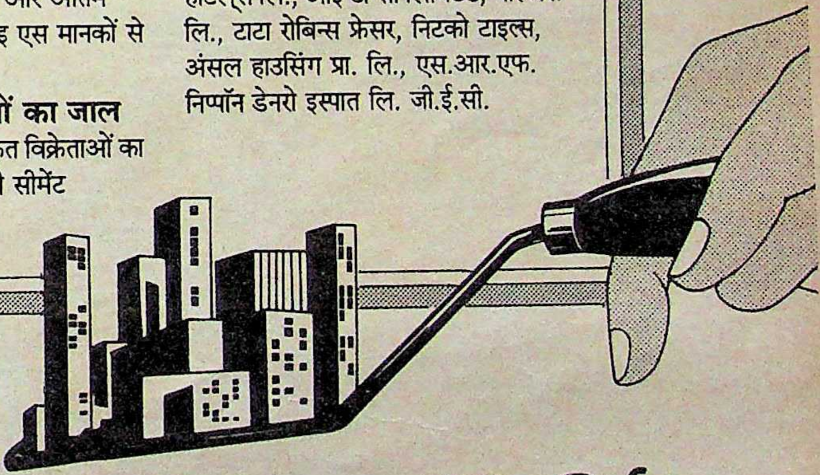

कैलाश सीमेंट : निर्माता

रेमण्ड

गुणवत्ता का दूसरा नाम.

जयराज, चरित्र अभिनेता

पं० नरेंद्र शर्मा महापुरुष थे

सन १९४६ में बाम्बे टाकीज की एक फिल्म बन रही थी, नाम तो उसका मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें मेरे साथ नायिका थी—देविका रानी। उस फिल्म के डायलाग लिखे थे भगवती बाबू (स्व० भगवती चरण वर्मा) ने। संगीतकार थे अनिल विश्वास और इसके गीत लिखे थे—पं० नरेंद्र शर्मा ने। इसी फिल्म से हमारी दोस्ती का बीज पड़ा था। दोस्ती का कारण था हम दोनों की एक जैसी रुचि। उनके सान्निध्य में आकर साहित्य की पुस्तकें पढ़ने का शौक मुझमें भी उत्पन्न हुआ था।

भगवती बाबू की कहानी 'प्रतिमा' पर जब मैंने फिल्म बनायी, तो उसमें भी संवाद भगवती बाबू के थे और गीत नरेंद्रजी ने लिखे थे। जाहिर था फिल्म के साथ-साथ हमारी दोस्ती भी बढ़ती गयी। बाम्बे टाकीज ज्वाइन करने के एक वर्ष बाद ही नरेंद्रजी का विवाह हुआ। उस समय वे बंबई के शिवाजी पार्क में रहते थे और मैं माटुंगा में, लेकिन हम अकसर मिलते रहते थे। हमारी बढ़ती मित्रता का ही परिणाम था कि हम दोनों ने आसपास (१९वां रास्ता, खार) में अपने-अपने घर बनाने के लिए जगह खरीद ली। हम दोनों ने एक साथ ही घर बनवाने का निर्णय भी किया, अतः साथ-ही-साथ मकान का मुहूर्त भी किया। शाम को जब वे आते, तो हम दोनों घर की सीढ़ियों पर ही बैठ जाते और घंटों न जाने कहां-कहां की बातें किया करते, यहां तक कि हमें समय का भी आभास नहीं हो पाता। बड़े तरन्नुम से वे अपनी नयी लिखी कविताएं भी सुनाते और उन पर राय लिया करते। अकसर हम जीवन-दर्शन पर बहस किया करते थे —जिंदगी क्या है? जीवन के बाद क्या होता है, मृत्यु के उस पार क्या है? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है। हमारी बहस का दूसरा महत्वपूर्ण विषय होता था—ज्योतिष। पंडितजी ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। मैंने उनसे ज्योतिष सीखी, लेकिन लाख चाहकर भी कविताएं लिखना नहीं सीख पाया।

मुझे उनकी जिस बात ने सर्वाधिक प्रभावित किया था, वह थी उनकी स्पष्टवादिता। वे किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं करते थे। जो कुछ कहना होता था, 'टू दी प्वाइंट' और संक्षेप में कहते थे। ऐसी स्पष्टवादिता कम ही लोगों में मिलती है। खास तौर पर इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहां हर बात बढ़ाचढ़ाकर शुरू की जाती है और वैसे ही खतम की जाती है। पंडितजी पं० जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेट्री रह चुके थे, अतः उनके बारे में, उनकी आदतों और प्रकृति के बारे में भी अकसर हमारी बातचीत होती।

अपूरणीय क्षति: पं० नरेन्द्र शर्मा

बाम्बे टाकीज बंद हो जाने के बाद पंडितजी ने दूसरे निर्माताओं-निर्देशकों तथा संगीतकारों से संपर्क किया और बड़ी जल्दी उनकी उनसे दोस्ती भी हो गयी। इन्हीं में से एक थे मराठी के जाने-माने संगीत निर्देशक-सुधीर फड़के। 'भाभी की चूड़ियां' फिल्म में सुधीर फड़के ने पंडितजी के लिखे गीत 'ज्योति कलश छलके...' की धुन बनायी थी। इसके अलावा पंडितजी ने कई अन्य फिल्मों में गीत लिखे। वे अपनी भाषा की शुचिता पर डटे रहे। यहां तक कि राजसाहब की फिल्म 'सत्यम, शिवम, सुंदरम' में भी समझौता नहीं किया। उनके गीतों के बोल साहित्यिक थे। उन्होंने राजकपूर को बड़ी कुशलता से कन्विंस करा लिया था। उन्होंने यह धारणा निर्मूल कर दी थी कि शुद्ध परिष्कृत शब्दवाले गीत लोकप्रिय नहीं हो सकते। हां, भाषा की इस क्लिष्टता को लेकर हमारी अकसर बहस होती। मैं उनसे कहता, "आप साहित्य की बातें करते हैं। साहित्य और फिल्मों का संबंध दूर का है।" साहित्य समझने के लिए लाइब्रेरी-कालेज जाना पड़ता है, इसलिए फिल्मों में साहित्य को लाना मुमकिन नहीं है—फिल्म मनोरंजन का माध्यम जो है। भाषा को लेकर तो हमारा विवाद अकसर होता ही रहता था।

पंडितजी बहुत बड़े साहित्यकार तो थे, लेकिन उससे भी बड़े वे महापुरुष थे। मुझ जैसे बहुतेरे उनके संपर्क में आकर साहित्य की पुस्तकें पढ़ने लगे थे। उनमें एक खासियत और भी थी—वे बोलते बहुत कम थे। मिलते तो बस हाल चाल पूछते, "तुम कैसे हो?" "ठीक है।" लेकिन जब बोलना शुरू कर देते, तो फिर लगातार बोलते ही जाते।

हम दोनों ने एक साथ अपने बच्चे और अपने बच्चों के बच्चों का खारवाले घर में रहने का सपना देखा था। जब मैं घर छोड़कर जाने लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, परंतु जब मेरा लड़का ही मेरे विरुद्ध हो गया, तो मैंने वहां रहना उचित नहीं समझा। तरह-तरह से उन्होंने राय दी। रामायण एवं महाभारत के बहुत सारे प्रसंग भी सुनाये, परंतु मेरा कहना था, "पंडितजी, आप विद्वान आदमी हैं। आप हर बात का उत्तर साहित्य और इतिहास में खोज सकते हैं, लेकिन मैं अदना जीव हूं। मेरा मानना है कि जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाये, तो उसे काट देना ही बेहतर है। जितने दिन जीना है, क्यों न शांति से जीयें।" वैसे कोई परेशानी होती थी, तो वे भी मुझसे सलाह-मशविरा लिया करते थे।

जिस दिन मैंने घर छोड़ा, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उनसे जाकर मिलूं। अतः मैं रात को चुपचाप अपनी बीवी के साथ बिना उनसे मिले ही चला आया। उसके बाद मेरा उनसे मिलना एक तरह से हुआ ही नहीं। मैं इतना क्षुब्ध था कि उस रास्ते से पूरे साल भर तक मैं गुजरा ही नहीं। बस, एक बार मुलाकात हुई थी, राज कपूर के देहांत के बाद चौथ पर। वह भी बड़ी औपचारिक। देखते ही वे बोले "कैसे हो?" मैंने भी वैसे ही जवाब दिया था "ठीक हूं।" वहां पर काफी भीड़ थी, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी थी। तब मुझे क्या पता था कि हमारी ४० वर्ष पुरानी दोस्ती की वह आखिरी मुलाकात थी। मुझे पता चला था कि कई बार उन्होंने याद किया कि जयराज से मिले बहुत दिन हो गये। लेकिन न वे ही मिल पाये, न मैं ही। उनके घर से कई बार फोन भी आया, उन्होंने पड़ोस के कुछ लड़कों को भेजा मुझे बुलाने के लिए भी। शायद यह मेरी जिद ही थी जो मैं उनसे मिल नहीं सका। मेरे सामने उनका निर्जीव शरीर पड़ा था—ठीक ४० वर्ष पहले जैसा सजीव, सचेतन। लगता था अभी उठकर वे अपनी कोई ताजी कविता सुनाने लगेंगे।

—बंबई ब्यूरो

पणछेन लामा

दलाई लामा

पणछेन लामा का निधन

अब चीन का रुख !

पणछेन लामा के निधन पर बीजिंग और दलाई लामा ने अपने-अपने ढंग से शोक का इजहार किया है। बीजिंग को दुख है कि उसका एक प्रबल समर्थक उठ गया, तो दलाई लामा दुखी हैं कि एक धार्मिक साथी और बीजिंग में बैठकर तिब्बत के अधिकारों की मांग को बल देने वाली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गयी है। दलाई लामा का दावा है कि पणछेन लामा तिब्बत की आजादी के लिए निरंतर संघर्षरत रहे। शायद यही वजह है कि कुछ तिब्बती क्षेत्रों में यह भावना दृढ़ हुई है कि पणछेन लामा की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या की गयी है।

५२ वर्षीय पणछेन लामा ने इधर बीजिंग को ही अपना स्थायी निवास बना रखा था। उन्होंने शादी कर ली थी। कहा जाता है कि उनके एक पुत्री भी है। उनकी मृत्यु शिगात्से (तिब्बत) में हुई जहां वे एक मठ का उद्घाटन करने गये थे। इस मठ में उनके पूर्ववर्ती पांच पणछेन लामाओं के अवशेष रखे हैं। शिगात्से में ही उन्हे दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गयी।

तिब्बत प्रेम: अक्तूबर १९४९ में जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया था, तब पणछेन लामा की उम्र १२ वर्ष थी। चीनियों का दावा है कि पणछेन लामा ने कम्युनिस्टों की जीत पर बधाई संदेश भेजा था। नवंबर १९४९ में बीजिंग रेडियो के एक प्रसारण में कहा गया था कि पणछेन लामा ने माओ झेदुंग (माओ से तुंग) के पास एक विशेष संदेश भेज कर उनसे अनुरोध किया था कि चीन को मुक्त कराने के बाद वे तिब्बत को भी मुक्त करायें। चीनियों का कहना है कि पणछेन लामा के इस अनुरोध के बाद ही १९५० में चीनी सेना ने तिब्बत पर हमला करके उसे मुक्त कराया था। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तिब्बत के भविष्य के बारे में वार्ता शुरू हुई। बीजिंग ने दलाई लामा पर दबाव डाला था कि वे पणछेन लामा को अपने समान स्तर का धर्मगुरु और तिब्बत का भौतिक नेता स्वीकार कर लें। यही नहीं, पणछेन लामा को दलाई लामा के प्रभाव से मुक्त करके उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से ही चीन के फौजी अधिकारी उन्हें ल्हासा के कुमबुम मठ से निकाल कर शिगात्से ले गये थे और वहीं १९५२ में उन्हें दलाई लामा की टक्कर के धार्मिक नेता के रूप में प्रस्थापित किया गया था।

पणछेन लामा १९५४ में दलाई लामा के साथ भारत भी आये थे। कहा जाता है कि चीनियों ने पणछेन को इसलिए भारत भेजा था, ताकि वे दलाई लामा पर नजर रख सकें। उन दिनों चर्चा थी कि दलाई लामा वापस तिब्बत जाना नहीं चाहते थे, पर उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा था। भारत नहीं चाहता था कि दलाई लामा को लेकर चीन से उसके संबंध बिगड़ें। बाद में तिब्बत की हालत इतनी बिगड़ी कि १९५९ में दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। बीजिंग सरकार ने तब पणछेन लामा पर दबाव डाला था कि वे दलाई लामा को सार्वजनिक रूप से देशद्रोही और धर्मद्रोही करार देकर स्वयं दलाई लामा बन जायें। पर पणछेन ने चीन के इस दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया था। १९६४ में तो उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करते हुए तिब्बत की आजादी का समर्थन भी किया था। चीन सरकार इस पर बेहद खफा हुई थी। उन्हें गिरफ्तार करके बीजिंग स्थित एक कारागार में डाल दिया गया। यह वह समय था जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति का दौर चल रहा था। १९७६ में सांस्कृतिक क्रांति का चक्र जब थमा और बीजिंग ने अपनी भूल को स्वीकार करके १९७८ से जब तिब्बत के प्रति समझौते का रुख अपनाना शुरू किया, तब फिर पणछेन लामा को महत्व दिया जाने लगा। चीन ने पणछेन लामा को आगे कर तिब्बत पर अपने अधिकार का औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की। १९८४ में पणछेन लामा को चीन की संसद, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया।

राजनीतिक महत्व: पणछेन लामा ने अपने बढ़ते राजनीतिक महत्व का इस्तेमाल तिब्बत के प्रति चीन की नीति को नरम बनाने के लिए किया। १९८७ में ल्हासा के दंगों के बाद तो वे इस बात को लेकर काफी सक्रिय रहे कि चीन के कट्टरपंथियों को तिब्बत में पुराने ढर्रे पर अत्याचार ढाने से रोका जाये। पणछेन ने अपने को बीजिंग समर्थक साबित करने के लिए यद्यपि उन तत्वों की कड़ी भर्त्सना की, जो ल्हासा में दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार थे, तथापि वे पहले तिब्बती नेता थे, जिन्होंने बीजिंग में बैठकर सार्वजनिक रूप से कहा था कि चीनी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाकर उनकी हत्या की है। दंगों के सिलसिले में चीन की सैनिक पुलिस ने ५९ लामाओं को गिरफ्तार कर लिया था। पणछेन लामा ने अपने प्रभाव का उपयोग करके उन्हें मुक्त कराया था। वे जब भी मौका पाते चीनी अधिकारियों को बताते रहते कि तिब्बत में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए चीन की अतीत की वामपंथी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। अतीत की इन भूलों के कारण ही तिब्बती जनता चीन को अपना रक्षक नहीं त्रासद मानती है।

वर्ष १४४७ में दलाई लामा ने पणछेन लामा की गद्दी स्थापित की थी। हाल में ही शरीर त्याग करने वाले पणछेन लामा इस गद्दी पर बैठे सातवें पणछेन लामा थे। १९४० तक पणछेन लामा कुछ धार्मिक और कुछ राजकीय रस्मों का निर्वाह करते थे। दलाई लामा की ही तरह पणछेन लामा के बारे में भी यह मान्यता है कि वे शरीर त्याग के बाद फिर जन्म लेते हैं। नवजात पणछेन लामा की खोज भी दलाई लामा की तरह की जाती है और दलाई लामा ही इसका निर्णय करते हैं कि कौन सा बालक पणछेन लामा का अवतार है। छठे पणछेन लामा तक यह परंपरा रही कि वे राजनीति से दूर रहते थे, पर चीन पर जापान का हमला होने के बाद चीनी शासकों ने तिब्बत की ओर ध्यान देना शुरू किया और सातवें पणछेन लामा को पहले च्यांग काईशेक और बाद में कम्युनिस्टों ने राजनीतिक महत्व देना शुरू किया। दलाई लामा १९११ की चीनी क्रांति और १९१४के शिमला समझौते के बाद से तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ कर रहे थे। दलाई लामा को काटने और कमजोर करने के उद्देश्य से चीन के शासकों ने पणछेन लामा को उछालना शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि दलाई लामा और पणछेन लामा के संबंधों में तल्खी आने लगी। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद दोनों नेताओं के बीच दूरी और बढ़ गयी थी।

चीन का सिरदर्द: पणछेन लामा के निधन के बाद चीन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अब वे स्वयं पणछेन लामा के अवतार की खोज करेंगे। पणछेन लामा के अवतार को लेकर तिब्बत के लोग चिंतित हैं, क्योंकि जहां चीन ने यह घोषणा कर रखी है कि वह धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगा, वहीं कुछ वर्ष पूर्व चीन ने यह भी स्पष्ट किया था कि भविष्य में अवतार और पुनर्जन्म जैसे अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। पणछेन लामा के निधन से जो स्थिति बनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए चीन क्या रुख अपनायेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु ज्यादा संभावना इसी बात की है कि चीन पणछेन लामा के अवतार को अस्वीकार नहीं करेगा और अवतार को मान्यता देने के दलाई लामा के अधिकार को भी खतम नहीं कर सकेगा। यदि चीन दलाई लामा द्वारा स्वीकार किये गये पणछेन लामा के अवतार को स्वीकार करेगा, तो क्या यह कदम चीन का झुकना और उसकी शिकस्त नहीं कहलायेगा ?

बहरहाल, पणछेन लामा के अवतार के संबंध में चीन का नजरिया क्या होगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, किंतु यह कहना गलत न होगा कि भले पणछेन लामा अपने जीवन में चीन के लिए परेशानी का कारण नहीं बने; किंतु शरीर त्याग कर उन्होंने चीन के लिए एक मुसीबत अवश्य खड़ी कर दी है।

—रामपाल सिंह

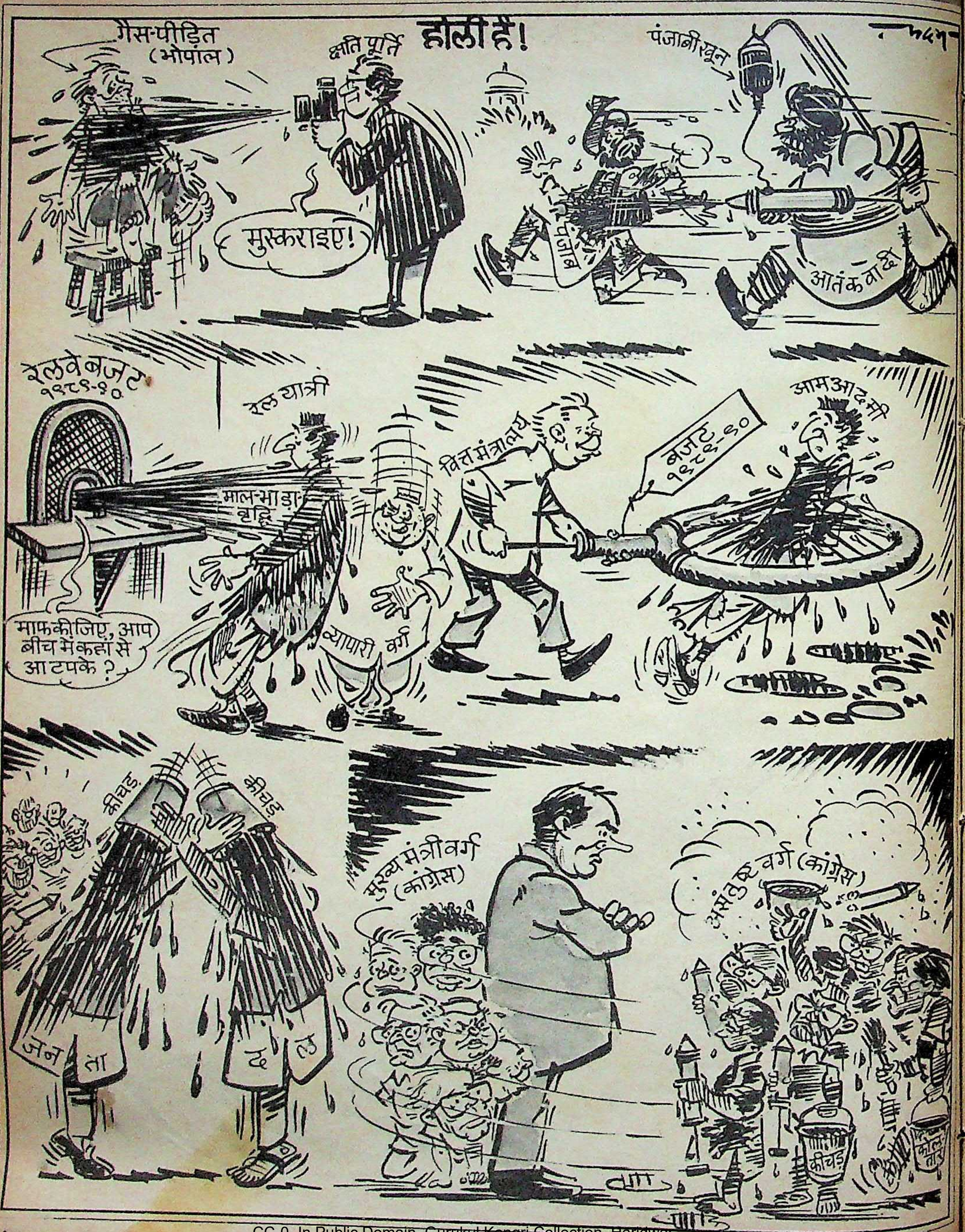
होली है!
गैस-पीड़ित (भोपाल)
क्षति पूर्ति
मुस्कराइए!
पंजाबी खून
पंजाब
आतंकवादी
रेलवे बजट १९८९-९०
रेल यात्री
माल-भाड़ा वृद्धि
माफ कीजिए, आप बीच में कहां से आ टपके?
व्यापारी वर्ग
वित्त मंत्रालय
बजट १९८९-९०
आम आदमी
कीचड़
कीचड़
जन ता दल
मुख्य मंत्री वर्ग (कांग्रेस)
असंतुष्ट वर्ग (कांग्रेस)
कीचड़
कोलतार

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

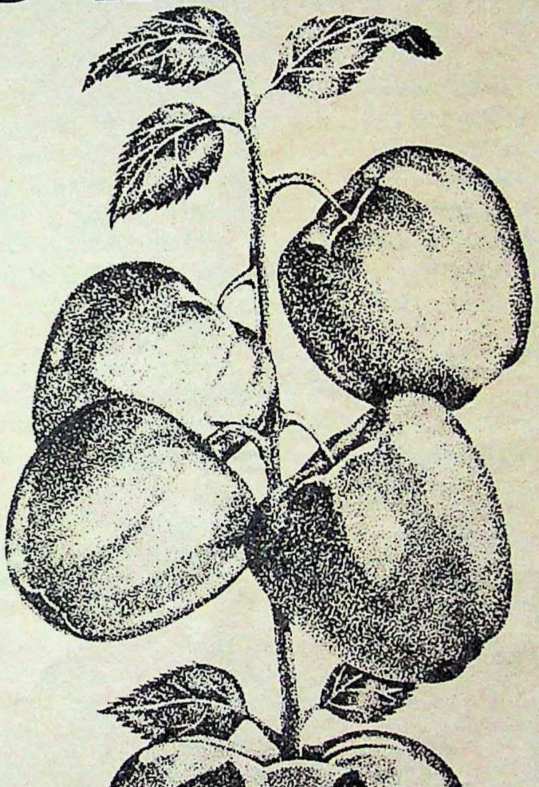

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

उद्योग की सेवा का 25 वाँ वर्ष

1964 · 1989

SILVER JUBILEE YEAR

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

जॉली मेकर चेंबर्स नं. 2, 225, विनय के. शाह मार्ग, नरिमन पॉइंट, बम्बई 400 021.

Sobhagya-B/89 HN

वसंत साठे उवाच

> **हैरानी की बात यह है कि एक तरफ सरकार महिलाओं की प्रगति और विकास का दम भर रही है, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में बेहतर हिस्सेदारी के लिए तैयार कर रही है, उनके लिए दीर्घकालीन राष्ट्रीय योजना बना रही है, दूसरी तरफ सरकार का एक प्रबुद्ध प्रवक्ता बड़े लापरवाह अंदाज में घोषणा कर रहा है कि कन्या शिशु की गर्भ में ही हत्या कोई गंभीर समस्या नहीं है।**

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री डाक्टर वसंत साठे ने हाल ही एक आयोजन में अपने भाषण में कहा कि गर्भ समापन और भ्रूण परीक्षण में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में अनिच्छित शिशु से छुटकारा पाना ही लक्ष्य है। समस्त स्वतंत्रचेता महिलाएं उनके इस वक्तव्य से बौखला गयी हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ सरकार महिलाओं की प्रगति और विकास का दम भर रही है, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में बेहतर हिस्सेदारी के लिए तैयार कर रही है, उनके लिए दीर्घकालीन राष्ट्रीय योजना बना रही है, दूसरी तरफ सरकार का एक प्रबुद्ध प्रवक्ता बड़े लापरवाह अंदाज में घोषणा कर रहा है कि कन्या शिशु की गर्भ में ही हत्या कोई गंभीर समस्या नहीं है। उनका मानना है कि जब महिलाओं की संख्या कम होगी, तो दहेज की समस्या का अपने आप समाधान हो जायेगा, पुरुष दहेज लेकर विवाह करने की जगह दहेज देकर विवाह करेंगे और स्त्री दुर्लभ होकर महिमा और महत्व कमायेगी। साठेजी के तर्कशास्त्र का तिर्यक मार्ग बड़े विकट संकेत देता है। इस तर्कशास्त्र के सती-दाह, दहेज-दाह, नारी-यातना सब को प्रच्छन्न समर्थन मिलेगा और स्त्री के प्रति अन्याय की एक नयी आचार-संहिता बनती जायेगी।

दरअसल ऊर्जा मंत्री महोदय के दिमाग में गर्भ समापन, भ्रूण-परीक्षण, कन्या-शिशु-वध जैसे अहम मसले सब गड्डमड्ड हो गये लगते हैं। इनके इस बयान से स्त्री की अस्तित्व की लड़ाई और भी विषम आकार ग्रहण कर लेगी। भारतवर्ष में पहले ही लडकियों की संख्या लड़कों से कम है। ऐच्छिक गर्भ समापन और भ्रूण-हत्या के बाद यह संख्या और भी कम हो जायेगी। क्या सरकार दहेज-समस्या का निराकरण इतने अजीबोगरीब बयान से करने का सपना देख रही है। सभी जानते हैं कि दहेज की समस्या जनसंख्या में नर-नारी अनुपात की विषमता के बावजूद दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। साठेजी ने जब यह कहा, वे भूल गये कि विवाह के बाजार में लड़की को घर में चीनी की बोरी की तरह तहखाने में डालकर तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता, जब तक लड़कों की कीमतें गिरने न लगें। एक वाजिब उम्र में लड़की का विवाह करना ही पड़ता है। दहेज के मूल में नर-नारी अनुपात का सिद्धांत कोई असर नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए क्योंकि वहां प्रलोभन-विवशता के सिद्धांत में प्रलोभन ही जीतता चला आ रहा है। दहेज जैसी राष्ट्र व्यापी समस्या का इतना हास्यास्पद समाधान सुझाना, सरकार के एक प्रबुद्ध प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। उचित ही है कि नारी विषयक सवालों को लेकर सक्रिय विचारकों, संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बयान पर आश्चर्य और क्रोध व्यक्त किया। 'स्त्री उवाच' की छाया दातार ने कहा, "महाराष्ट्र सरकार ने गर्भस्थ शिशु के लिंग-परीक्षण पर निषेधात्मक आदेश पहले ही पारित कर दिया हैं, केंद्र में भी इस पर विचार हो रहा है, ऐसे में एक वरिष्ठ मंत्री का इसके पक्ष में वक्तव्य देना हैरानी की बात है।" एआईडीडब्ल्यूए की संयुक् सचिव वृंदा करात ने भी श्री साठे के वक्तव्य का विरोध कि और कहा, "भ्रूण का लिंग पता चलने के बाद भ्रूण-हत्या क निर्णय लिया जाता है जो कि गलत है। इस तरह के गर्भ-समापन की जड़ में यह धारणा बैठी हुई है कि लड़की परिवार के ऊप एक बोझ है। साठेजी की सरकार ने स्वयं नर-नारी अनुपात प काफी चिंता प्रकट की है। सामान्य रूप से आज भारत में प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे ९३३ नारियां हैं। वसंत साठे के बयान का आशय तो यह निकलता है कि अगर हिंदुस्तान में जनसंख् की रोकथाम करनी है, तो एटमबम गिराकर यह काम क लिया जाये।"

कभी-कभी ऐसा लगता है कि समाज में स्त्री का संघ एक विषम चक्र में फंस गया है। संघर्ष और क्रांति के प ऊर्ध्वगामी होते हैं, तो गति और अवरोध का स्पष्ट पता चलत है, लेकिन विषम चक्र में पड़ा संघर्ष अपने सेनानियों को थक मारता है। लोग उसे एक तमाशा समझ कर देखते हैं और भू जाते हैं। कहां पौराणिक काल में शकुंतला, द्रौपदी और सीता व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, कहां बीसवीं शताब्दी के अंति दशक में हम अभी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिंदा रहने मौलिक मानवीय अधिकार के लिए आज स्त्री को अपन आवाज उठानी पड़ रही है और पुरुष बड़े आराम से कुरसी प बैठा-बैठा समझा रहा है "क्यों शोर मचा रही हो, चुपचा मरती रहो, हम तुम्हें तुम्हारा जातीय गौरव दिलाकर रहेंगे। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है कि स् की जीने की मांग भी एक नारीवादी शोर मान कर टाल दि जाये।

इस बिंदु पर हमें खुद अपने से मुखातिब होना जरूरी है आखिर जीने की मांग औरत किससे कर रही है और क्यों ? ग समापन और भ्रूण-हत्या में स्त्रियां पुरुषों से कम गुनहगार न हैं। प्राय: यह देखा गया है कि गर्भावस्था में कोई असामान् लक्षण न होने पर भी आसन्न प्रसवा मां भ्रूण-परीक्षण के लि पति से आग्रह करती है और जानना चाहती है कि उसकी को में बेटा है या बेटी। वह परिवार में बेटे की मां के रूप में प्रतिष्ठ पाना चाहती है। गर्भ में कन्या-शिशु का पता लगते ही वह कि तरह उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचती है। ऐसे समय ग समापन में उसकी पूर्ण सहमति होती है। वह यह भूल जाती कि कन्या-शिशु को खतम कर वह स्वयं अपने जीवन के समा अवसर खतम कर रही है। दूसरों से गौरव लेने के लिए पह अपने आपको गौरव देना जरूरी होता है। स्त्रियों को ऐसे निर्ण नहीं लेने चाहिए जो खुद उनके विरुद्ध पड़ें और जिनसे उनक अस्तित्व औरों की अनुकंपा से चालित होने का भ्रम पैदा हो

बात घूम फिर कर शिक्षा पर आ जाती है। लड़कियों को उचित शिक्षा दिये बगैर उन्हें अस्तित्व, व्यक्तित्व और अस्मित के निर्माण के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इस वर्ष शिक्ष विभाग ने कालेजों में जनसंख्या शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ कर इस दिशा में एक पहल की है। देखना यह है कि कितनी संस्थाएं सचमुच इस प्रशिक्षण को कार्यान्वित करती हैं।

—ममता कालिया

ईमानदार गरीबी

लालच तो ऐसी चीज है कि भाई को भाई से अलग कर देता है, गैरों की कौन कहे ! जहां लोग एक-एक पैसे के लिए एक दूसरे को ठगने के लिए तैयार बैठे हों, वहां लाखों रुपए के हार को पाकर भला कौन खोना चाहेगा ? लेकिन बेईमानी का दुर्भेद्य अंधकार ईमानदारी के जुगनू को चमकने से नहीं रोक सकता। बलिया का प्रेरक प्रसंग इसी का द्योतक है।

दरअसल हुआ यह कि बलिया के सहतवार कस्बे में चाय की दुकान पर बातचीत में जानुद्दीन नाम का एक आदमी कागज में लिपटा हुआ एक सोने का हार भूलकर चला गया। जब वह घर पहुंचा और उसकी घरवाली ने हार के बारे में दरियाफ्त किया, तो उसके तो होश फाख्ता हो गये। वह भागा-भागा दुकान पर पहुंचा। दुकानदार द्वारा अनभिज्ञता प्रकट करने पर उसकी चायवाले से अच्छी खासी तू-तू, मैं-मैं हो गयी। देखते-देखते वहां भारी भीड़ जुट गयी। नौबत कसम खाने-खिलाने तक पहुंची ही थी कि उतने में चायवाले की मां निकल पड़ी और उसने जानुद्दीन से हार का हुलिया पूछा। उसे जब लगा कि हार इसी आदमी का हो सकता है, तो उसने हार वापस कर दिया। बुढ़िया से यह पूछने पर कि हार मिलने की खबर किसी और को क्यों नहीं दी, तो उसने बताया कि उसको डर था कि उसके कई नकली दावेदार तैयार हो जाते। जानुद्दीन ने इनाम के तौर पर बुढ़िया को सौ रुपए का एक नोट देना चाहा, तो उसने यह कह कर इनकार कर दिया कि बेटा, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत पर भरोसा करते हैं। पैसे की ललक होती, तो सोने का हार ही नहीं रख लेते।

हिटलर को सजा

वैसे तो किसी के नाम में कुछ नहीं रखा है और किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी-कभी नाम का इतना असर होता है कि व्यक्ति उसी के अनुरूप काम भी करने लगता है। अब फ्लोरिडा के जेक्सनविले के १८ वर्षीय एडोल्फ हिटलर क्लार्क को ही ले लीजिए, जिसे एक हत्या के मामले में दस साल की सजा हो गयी है। उसका कहना है, "मैं अपने नाम की वजह से ही अपराधी बना। जब मुझे तानाशाह हिटलर के बारे में जानकारी मिली, तो मैंने वैसा ही बनने की कोशिश की।" उल्लेखनीय है कि १६ साल की उम्र से ही उसने स्कूल से भागना और चोरी करना शुरू कर दिया था। इधर उसने अपने एक अन्य साथी एंथोनी माइकल के साथ मिलकर २ अगस्त '८६ को एक ३५ वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी जिसके जुर्म में उसे दस साल और उसके अपराधी साथी माइकल को अदालत ने १५ वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।

क्लार्क के पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम हिटलर इसलिए रखा था, क्योंकि वह इतिहासप्रसिद्ध व्यक्ति था।

तकिये के सहारे उड़ चला

दूरदर्शन वाले दूरदर्शन पर सुपरमैन, ही मैन तथा स्पाइडरमैन जैसे सीरियलों को प्रदर्शित कर सोचते हैं कि वे नयी पीढ़ी का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इन सीरियलों का अनुकरण कर बच्चे कैसे अपनी जान गंवाने का खुद उपक्रम कर बैठते हैं, इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही देखने को मिला है। अमरीका के वेस्ट लाइन में रहनेवाले एक तीन वर्ष के बच्चे ने इन फिल्मों की देखादेखी हवा में उड़ने की सोची। बिना आगा-पीछा सोचे वह जिस तकिये का सहारा लेकर बैठा था, उसी को हाथ में लेकर अपने दोमंजिला मकान की खिड़की से उड़ान भरने की कोशिश की। यह कहानी तो थी नहीं कि वह उड़ने लगता। यह तो वास्तविकता थी, सो हुआ क्या कि वह २५ फुट नीचे आ गया। लेकिन गनीमत थी कि वही तकिया उसके लिए कवच बन गया, तकिया नीचे और वह उसके ऊपर गिरा, सो चोट नहीं आयी। लेकिन वह अपने उड़ने के सपने बिखर जाने से दहाड़ मारकर रो रहा था। जब उसकी मां ने उसकी आवाज़ सुनी, तो बाहर निकली। किसी तरह उसे चुप कराया, फिर अस्पताल ले गयी, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वह स्वस्थ था।

शौर्यपदक से एक किलो प्याज

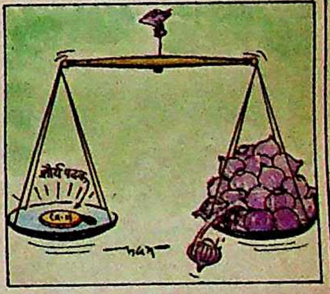

यों तो हमारी सरकार आये दिन किसी-न-किसी रेजीमेंट की वर्षगांठ मनाकर एक से एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहती है और ऐसे कार्यक्रमों में अकसर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री मुख्य अतिथि हुआ करते हैं, लेकिन सीमाओं पर रात दिन प्रहरी बने सैनिकों और देश की आन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करनेवाले पूर्व सैनिकों की दुर्दशा पर शायद कोई ध्यान नहीं देता। कदाचित उसी का कुफल है कि एक सैनिक को युद्ध में वीरता के लिए प्रदान किये गये शौर्यपदक से एक किलो प्याज खरीदनी पड़ी।

सुनने में बात झूठ लगती है, लेकिन गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित नेताजी सुभाष स्मारक समिति के महासचिव अशोक कुकरेजा ने पिछले दिनों वह शौर्यपदक एक स्थानीय सब्जी विक्रेता से महज चार रुपए में खरीदा, जिस पर एक तरफ उस सैनिक का नाम 'जेसीओ भोपाल सिंह १८०३४३, राजपूत राइफल्स,' अंकित है, तो दूसरी तरफ 'स्वतंत्रता की २५वीं वर्षगांठ अंकित' है। कुकरेजा ने इस पदक के बारे में प्रधानमंत्री और थलसेना अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन कारणों का पता लगाने का अनुरोध किया है कि ऐसी कौन-सी वजहें थीं कि उस जांबाज सैनिक को एक किलो प्याज के लिए अपना शौर्यपदक बेचना पड़ा।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

नसीरुद्दीन शाह

समांतर सिनेमा से व्यावसायिक फिल्मों तक

श्याम बेनेगल की फिल्म 'निशांत' ने जिन प्रतिभाशाली कलाकारों को जन्म दिया, उनमें से एक हैं, नसीरुद्दीन शाह। पिछले पंद्रह वर्षों में नसीर नंबर वन स्टार तो नहीं बन सके, लेकिन नंबर वन अभिनेता जरूर बन गये जिन्हें सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय ख्याति, पुरस्कार और सम्मान (सत्यजित रे के बाद) मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए उन्होंने सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार भी बटोरे।

"लोग ऐसा समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ मुझे श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक की फिल्में ('निशांत', 'मंथन', 'भूमिका', 'जुनून', 'मंडी', 'त्रिकाल' आदि) एक के बाद एक मिलती चली गयीं, तो दूसरी तरफ मैंने तय कर लिया था कि मुझे बेहतर फिल्में ही करनी हैं, क्योंकि यही मेरी शख्सीयत, मेंटेलिटी (मानसिकता) और वैचारिकता को 'शूट' करती थीं।" नसीर ने 'माया' को बतलाया, "लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने संघर्ष नहीं किया। यहां आने के पहले मैंने काफी संघर्ष किया था। मैं दिमागी तौर पर जुनूनी आदमी हूं, जो तय कर लेता हूं, उसे हासिल करके ही रहता हूं देर भले ही लग जाये उसे पाने में।"

नसीर आज भी दिल्ली की संघर्ष-यात्रा को याद कर रोमांचित हो उठते हैं जब उन्हें एक-एक पल जिंदगी की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपनी 'आकांक्षा और सपने' के कांच के बने दर्पण को चटखने से बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन फाकेमस्ती, अभाव और तनाव के चरम शिखर पर पहुंच कर भी वे वापस लौटने के लिए तैयार नहीं रहे—भीतर की आग हमेशा उन्हें प्रज्ज्वलित करती रही।

"जब पूना इंस्टीट्यूट में यह लड़का मुझे मिला, तो पहले लगा कि उसके भीतर गरूर जरूरत से बहुत ज्यादा हैं," गिरीश कर्नाड बतलाते हैं, "लेकिन मैंने जब इसका काम देखा, तो लगा यह गरूर इसकी शख्सीयत है, जबकि भीतर से यह पानी से भी कहीं अधिक तरल इंसान है। श्याम बेनेगल ने जब मुझसे 'निशांत' के लिए नये कलाकारों की बात की, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में नसीर का चेहरा और नाम ही सामने आया था। उसके बाद जब मैंने 'गोधूलि' बनायी, तो उसे ऐसी भूमिका देने का निश्चय किया, जो उसके बाहरी मिजाज से एकदम विपरीत थी। नसीर के अभिनय पर उसका मिजाज कभी हावी नहीं होता, इसीलिए उसने 'गोधूलि' में कट्टरपंथी ब्राह्मण की भूमिका को बड़े प्रभावशाली ढंग से अभिनीत किया था। मैंने तभी उससे कहा था, नसीर, आनेवाला कल तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम आज के सशक्त अभिनेताओं की तरह अपनी निजी इमेज को अपने किरदार पर कभी हावी नहीं होने देते।"

"गिरीश कर्नाड ने जब नसीर को पहली बार मेरे पास भेजा, तो मेरे कुछ सहायकों ने कहा कि यह जमींदार के भाई की भूमिका भला कैसे निभायेगा, इसकी आंखों तथा चेहरे पर 'जमींदाराना लुक' तो है ही नहीं।" श्याम बेनेगल ने 'माया' को बतलाया, "लेकिन गिरीश की ही तरह मैंने भी नसीर की आंखों और दिल के भीतर छिपे अभिनय की आग को देखा और उसका रोल मुकर्रर कर दिया।"

'निशांत', 'अंकुर' की तरह बाक्स आफिस पर सफल नहीं हुई थी, इसलिए दूसरा कोई निर्माता उन्हें काम देने के लिए न तो आगे आया और न ही नसीर ने कोशिश की। इस बीच श्याम बेनेगल निर्देशित नसीर की 'भूमिका' तथा 'मंथन' ही प्रदर्शित हो सकी, लेकिन श्याम की तीनों फिल्मों ('निशांत', 'भूमिका' और 'मंथन') में नसीर सिर्फ एक किरदार रहे—ढेर सारे कलाकारों के बीच एक कलाकार। १९७८ में गोविंद निहलानी के 'आक्रोश' ने, जिसमें उनके साथ ओमपुरी ने भी पहली बार काम किया था, जरूर एक नयी जमीन दी जिसे प्रभावशाली ढंग से पुख्ता किया 'जुनून' ने, जिसमें एंग्रीमैन की उनकी एक नायाब तस्वीर बनी, फिर आयी सईद मिर्जा की 'अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है' तथा रवींद्र धर्मराज की 'चक्र', विधु विनोद चोपड़ा की 'सजाये मौत' तथा मुजफ्फर अली की 'उमराव जान'।

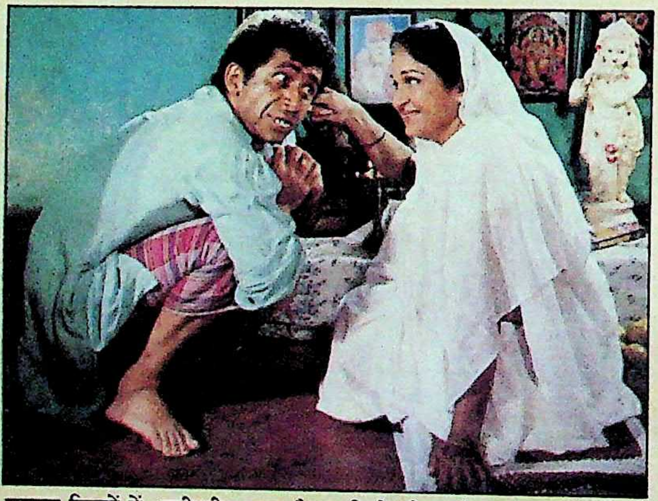

मसाला फिल्मों में: नसीरुद्दीन शाह और कामिनी कौशल फिल्म 'जलवा' में

एंग्रीमैन की भूमिका में नसीरुद्दीन शाह

कलात्मक उपलब्धियों का वर्ष: १९८२ से ८५ तक का समय नसीर की कलात्मक उपलब्धियों का वर्ष साबित हुआ, जब उनकी 'बाजार', 'आधारशिला', 'अर्द्धसत्य', 'कथा', 'मंडी', 'जाने भी दो यारो', 'स्पर्श', 'खंडहर', 'मोहन जोशी हाजिर हो' तथा 'पार' व 'होली' प्रदर्शित हुईं। १९८५ के बाद कला फिल्मों के पराभव का जो काल शुरू हुआ, उसने नसीर को भी प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप १९८६ में 'एक पल' (कल्पना लाजमी), १९८७ में 'मिर्च मसाला' (केतन मेहता) तथा १९८८ में 'पेस्टनजी' (विजया मेहता) भर प्रदर्शित हो

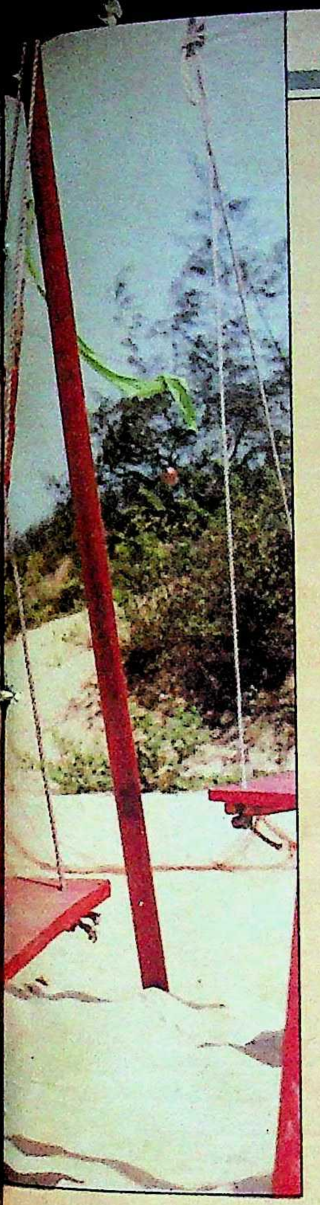

सकी। कला फिल्मों में नसीर ने जो स्थान बनाया, वह अपने अभिनय के बल-बूते पर बनाया था, संभवतः श्याम बेनेगल से लेकर मुजफ्फर अली तक ने उन्हें अगर नायक प्रधान फिल्मों में लिया होता, तो शायद शबाना और स्मिता के साथ-साथ वे भी उस स्टारडम की ऊंचाई तक पहुंच गये होते, जो कला फिल्मों के कलाकारों को आम तौर पर मयस्सर नहीं होता।

"नसीर अपने रोल को सही ढंग से पोर्ट्रेट करना जानते हैं," नसीर को लेकर 'होली', 'मिर्च मसाला' तथा 'हीरो हीरालाल' जैसी फिल्में बनानेवाले केतन मेहता बतलाते हैं, "इस मामले में वे दूसरे स्टारों से अलग हैं। दूसरे सितारे जहां करेक्टर को अपनी शख्सीयत तथा इमेज से जोड़ने की खातिर करेक्टर में ही उलट-पुलट कर देते हैं, वहीं नसीर करेक्टर के मुताबिक अपने भीतर उलट-पुलट करते हैं।"

"मिर्जा गालिब सीरियल बनाते समय हमें ऐसा लगता था कि हम नसीर से नहीं, जनाब गालिब से बातें कर रहे हैं।" गुलजार बतलाते हैं, "'मिर्जा गालिब' बनाने के पहले जितना रिसर्च हमने किया था, उससे कहीं ज्यादा खोजबीन तथा अध्ययन नसीर ने किया था मिर्जा गालिब के बारे में।"

एक बार ओमपुरी ने नसीर पर टिप्पणी की थी—"वह जब कोई फिल्म कर रहा होता है, तो लगता है यह फिल्म फिल्म नहीं, उसकी बीवी हो। लेकिन अब उसने इससे (कला फिल्मों) तलाक देकर दूसरी बीवी (कार्मशियल सिनेमा) के चंगुल में खुद-ब-खुद फंस गया है, उसी से अब उसका अफेयर चल रहा है।..."

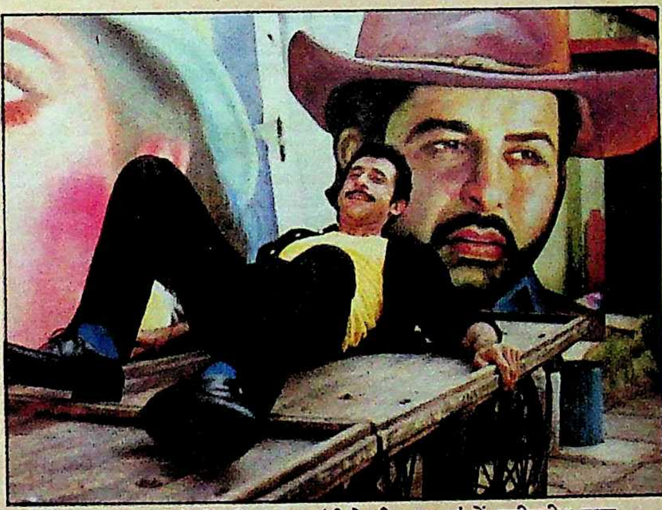

कमेडीवाली भूमिकाओं में भी सफल: 'हीरो हीरा लाल' में नसीरुद्दीन शाह

व्यावसायिक सिनेमा की ओर: ओमपुरी की इस टिप्पणी ने नसीर के मर्म को कितना आघात पहुंचाया होगा, कितनी बौखलाहट पैदा की होगी, उसका पता पिछले वर्ष तब लगा, जब उन्होंने श्याम बेनेगल से लेकर मृणाल सेन तथा कला फिल्म आंदोलन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थीं। १९८८ में उनकी जितनी फिल्में ('मालामाल', 'हीरो हीरालाल', 'परफेक्ट मर्डर', 'जुल्म को जला दूंगा', 'पेस्तनजी', 'इजाजत' आदि) प्रदर्शित हुई थीं, उतनी किसी भी कार्मशियल कलाकार की नहीं। इनमें से अगर एक भी बाक्स आफिस पर 'कयामत से कयामत तक' या 'तेजाब' जैसी व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर लेतीं, तो वे अनिल कपूर या आमीर खान की तरह स्टारडम की देहरी पर खड़े होते।

"नसीर में स्टारडम की सारी विशेषताएं मौजूद हैं" नसीर के साथ सर्वाधिक फिल्में करनेवाली शबाना आजमी का कहना है, "मेरी या स्मिता की तरह अगर उन्होंने शुरू से ही कला फिल्मों के साथ-साथ कार्मशियल फिल्मों में भी काम किया होता, तो निःसंदेह वे स्टार बन गये होते।"

'हम पांच', 'तजुर्बा', 'बेजुबान', और 'स्वामीदादा' फिल्मों की असफलता से लगा कि व्यावसायिक फिल्में नसीर को रास नहीं आ रही हैं। उनकी नियति सिर्फ कला फिल्मों तक ही है। पर ऐसे समय 'मासूम' ने नसीर के व्यावसायिक कैरियर में एक तरह से जान फूंक दी। फिर आयी बापू निर्देशित 'वोह सात दिन'। इसके बाद एक तरफ जहां 'मिसाल', 'सुर्खियां', 'शर्त', 'मान-मर्यादा' जैसी स्तरहीन फिल्में आयीं, तो दूसरी तरफ 'कर्मा' तथा 'जलवा' जैसी फिल्में भी जिन्होंने उनके भीतर की स्टार क्वालिटी को उभारने में पूरी सहायता की। दिलीप कुमार जैसे अभिनेता का सामना नसीर ने बड़ी सहजता, लेकिन पूरी तैयारी से किया। हमेशा गंभीर तथा एंग्रीमैन जैसी भूमिकाएं करनेवाले नसीर ने 'जलवा', 'मालामाल' तथा 'हीरो हीरालाल' में हास्यपरक अभिनय कर अपनी बन रही इमेज को तोड़ने की कोशिश भी की।

"लेकिन क्या इन स्तरहीन फिल्मों का चुनाव गलत नहीं था?" पूछने पर नसीर बोले, "दरअसल हमारे सामने स्क्रिप्ट होती है, उससे कभी-कभी फिल्म का अंदाजा नहीं लग पाता। जैसे 'सजाये मौत' की सिक्रप्ट पढ़ कर मुझे लगा कि यह मेरी जिंदगी की बेहतरीन फिल्म होगी, मैंने काफी मेहनत भी की, लेकिन पूरी होने पर फिल्म बेजान निकली। 'मासूम' मैंने बेमन से किया, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बन गयी। मृणाल सेन बहुत अच्छे निर्देशक हैं, लेकिन 'जेनेसिस' में वह प्रभाव पैदा नहीं कर पाये। केतन मेहता के साथ मैंने 'होली' और 'मिर्च मसाला' में काम किया था, मुझे पूरा विश्वास था कि 'हीरो हीरालाल' बढ़िया फिल्म बनेगी, लेकिन वे इसे पूरी करने में जल्दबाजी कर गये, यही हाल 'मालामाल' का था। हां, 'जुल्म को जला दूंगा' साइन कर मैंने गलती की थी।"

लेकिन शबाना, स्मिता पाटील, रेखा जैसी कुशल अभिनेत्रियों के साथ काम करने के बाद नीलम तथा सोनम जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम करने की क्या तुक? कहीं नसीर उन व्यावसायिक फिल्मों के चक्रव्यूह में तो बुरी तरह नहीं उलझ गये, जिनकी कभी वे तीखी आलोचनाएं किया करते थे? इस सवाल पर वे बौखलाना नहीं चाहते—'रेखा, शबाना, स्मिता का निस्संदेह कोई जवाब नहीं है। उनके साथ काम करते समय जोखिम भी नहीं रहता, साथ ही एक चुनौती भी बनी रहती है। लेकिन सोनम या नीलम नयी होने अथवा कार्मशियल सिनेमा की स्टार होने के कारण बुरी अभिनेत्री हैं, ऐसा क्यों सोच लेते हैं आप? जितने भी महान कलाकार हुए हैं, उनमें अधिकांश इसी तथाकथित कार्मशियल सिनेमा की देन हैं। अभी तक उन्हें कोई अच्छा रोल या डायरेक्टर नहीं मिला, जब मिलेगा तो वे भी अपना जौहर जरूर दिखलायेंगी।"

—रवींद्र श्रीवास्तव

अमिताभ : संवाद की सार्थकता

अपनी तेजाबी सफलता से चमत्कृत हो अनिल कपूर ने जहां अपना रेट एकबारगी १५ लाख से बढ़ाकर ३५ लाख रुपए कर लिया, वहीं अमिताभ बच्चन ने अपना रेट २० लाख रुपए घटा दिया। उनका कोई भी निर्माता आजकल अपनी फिल्म पूरी कर रिलीज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन केसी बोकाड़िया ऐसे में आगे आये और अमिताभ को लेकर 'कौन सुने फरियाद' का निर्माण शुरू कर दिया।

शूटिंग के पहले दिन ही अनिरुद्ध तिवारी लिखित जो डायलाग उन्होंने अमिताभ को बोलने के लिए दिया, वह कुछ इस तरह का था—'ठाकुर, बंदूक उठाने का मौका तुम्हें भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें इंतजार करना होगा। मैंने सात साल इंतजार किया...' इत्तिफाक से बगल के सेट पर राज बब्बर भी शूटिंग कर रहे थे। अतएव एक मसखरेबाज ने उन्हें देख कर अमिताभ बच्चन के उक्त संवाद को नेताई अंदाज में कुछ इस तरह दुहराया—'ठाकुर (विप्र सिंह), बंदूक उठाने (चुनाव लड़ने) का मौका मैं भी तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी नहीं (क्योंकि तुमने अपना बोफोर्स तोप सामने तान रखा है)। तुम्हें इंतजार करना होगा (चुनाव के ऐलान का)!...' उस डायलाग का मुलाहिजा किस तरह फरमाया अमिताभ बच्चन तथा राज बब्बर ने अपने अगल-बगल के मेकअप रूमों में, यह तो वे ही बतला सकते हैं।

दीपिका : चेहरे की दमक का राज

'रामायण' सीरियल में कम पारिश्रमिक मिलने के कारण रामानंद सागर से सख्त नाराज दीपिका का चेहरा अब पापाजी (सागर) को देखते ही पहले की तरह दमक उठता है। जब इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के स्थगन आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने 'उत्तर रामायण' के प्रदर्शन की अनुमति दी थी, तब सागर से कहीं ज्यादा खुश हुई थीं—दीपिका, क्योंकि इन एपीसोडों के लिए उन्होंने काफी 'टेंस' दृश्य दिये थे। लेकिन उससे भी ज्यादा तनाव में वे इसलिए थीं कि आगे से हर तरह के गलैमरस दृश्य करने के लिए तैयार होने के बावजूद कोई फिल्म निर्माता उनके पास नहीं फटका। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आये पापा सागर ही।

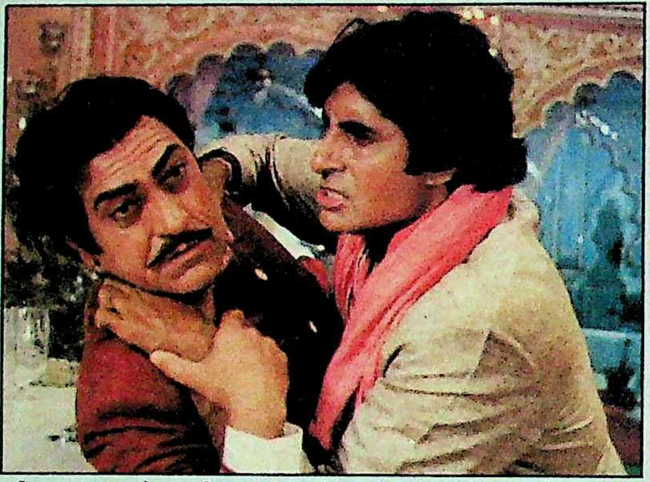

अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी फिल्म 'कौन सुने फरियाद' में

देवी-देवताओं की दर्शन-यात्रा पर निकले रामानंद सागर जब पालनपुर (गुजरात) स्थित अंबा देवी के मंदिर पहुंचे और अंबाजी की महिमा के बारे में सुना, तो उन्होंने तुरंत उन पर एक बड़े बजट की भव्य फिल्म की घोषणा कर दी। अब अंबाजी की भूमिका के लिए रूठी बेटी दीपिका से भला कौन उचित अभिनेत्री हो सकती है!

बस दीपिका के चेहरे पर हर क्षण खिली रहनेवाली ताजी मुस्कान का यही राज है!

भाग्यश्री का धमाका

छोटी-सी उम्र में, कच्ची धूप की तरह खिली मासूम किशोरी भाग्यश्री को सुर्खियों में रहने की कला खूब आती है। ताराचंद बड़जात्या जैसे बुजुर्ग निर्माता के सामने धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन और राखी जैसे कलाकार तथा मशहूर निर्देशक बासु चटर्जी तक सिर उठाकर बात करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन १६ वर्षीय भाग्यश्री ने उनकी फिल्म 'प्यार किया मैंने' साइन करने के पहले ही अपनी तमाम शर्तें पेश कर उनके सारे स्टाफ को हैरत में डाल दिया था। फिर इसके बाद 'दूसरी किसी भी फिल्म में काम नहीं करूंगी' का दूसरा फतवा दे कर वह पुनः चर्चा का केंद्र बन गयी थी, जब बंबई तथा मद्रास फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े निर्माता उसे बड़े सितारों के साथ साइन करना चाहते थे।

फिल्म से संन्यास ले विदेश उच्च अध्ययन का एलान करने वाली भाग्यश्री अमरीका में किसी कालेज में नाम लिखाने के बजाय एक दिन चुपचाप रजिस्ट्रार आफ मैरेजेज के दफ्तर में पहुंच गयी और वहां पर अपना नाम लिखा हस्ताक्षर कर दफ्तर के बाहर अपने साथी के साथ निकली, तो उसके हाथ में कालेज के सर्टिफिकेट के बजाय विवाह का सर्टिफिकेट था।

अब ताराचंद बड़जात्या ने जो कुछ भी सोच कर अपनी फिल्म का नाम 'प्यार किया मैंने' रखा हो, लेकिन उसे असल जिंदगी में ढाल कर भाग्यश्री फिर सुर्खियों का विषय गयी है!

छाया : सैयद बाकराह

भाग्यश्री फिल्म 'प्यार किया मैंने' में

देव आनंद का मुकद्द

हमेशा अपनी फिल्में पत्रकारो साथ बैठकर देखने के आदी आनंद जब 'सच्चे का बोलबाला', पत्रकारों की जिंदगी पर आधारि है, के प्रेस शो में दिखलायी नहीं प तो पत्रकारों का अचंभित हो वाजिब था। सो पत्रकारों के फो देव आनंद के घर पर डायल होने ल लेकिन उस समय वे अपने वकीलों साथ कानूनी जद्दोजहद से जूझ रहे क्योंकि जाने-माने फायनेंसर देवीदा जे थडानी ने बंबई उच्च न्यायालय मे एक याचिका दायर कर उनकी दोनों फिल्मों ('सच्चे का बोलबाला' तथा 'अव्वल नंबर') के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। थडानी ने उन्हें २२ दिसंबर '८४ को २३ लाख ५३ हजार रुपए फिल्म निर्माण के लिए कर्ज दिये थे और देव आनंद को मय ब्याज के २८ लाख रुपए थडानी को लौटाने थे। इसलिए उन्होंने यहीं बेहतर समझा कि प्रेस शो में न हों जायें।

—अखबारी लाल

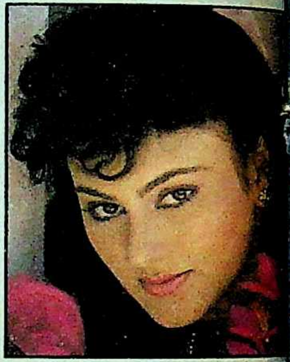

फिल्म 'अम्बाजी' में दीपिका

देवआनंद

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस, ३-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

धूम मचा दे... रंग जमा दे.
PAN PARAG
पान पराग
स्वादिष्ट
सादे पान का मसाला
पान मसाला

आपका मनपसंद पान पराग, डिब्बे और सुविधाजनक पाउच में.

अब स्वादिष्ट पान पराग जैसे चाहें वैसे लीजिए. डिब्बे या पॉकेट पाउच में... जहाँ जी चाहे ले जाइए — लुत्फ़ उठाइए. और पसंदीदा पान पराग के साथ ज़िंदगी की मौज-मस्ती का मज़ा लीजिए.

पान पराग®
पान मसाला

भारत का सब से अधिक बिकने वाला पान मसाला

कोठारी उत्पादन

everest/d89/KP/15 hin

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

-५।५।१८

MADONNA
आराम
सहारा
स्वास्थ्य
RILAXON
ISI
"मेरे आराम की दुनिया..."
Moonmoon Sen
(मुनमुन सेन)
SOBHAGYA (C) RIL/4/89/H

दिनभर की भागदौड़ और कड़ी मेहनत के बाद, शरीर एवं मन को चाहिए पूरा आराम। तनाव से मुक्त आराम।
जब आराम की बात है तो रिलैक्सॉन मैट्रेस ही हमसब की पहली पसन्द है।
रिलैक्सॉन के मैट्रेस, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, वैज्ञानिक ढंग से, प्राकृतिक रबराइज़्ड़ कोयर फाइबर से बनाये जाते हैं, जिससे भरपूर सहारा एवं आराम मिलता है।

RILAXON
आपके आराम के लिए
मैट्रेस, कुशन, तकिया, अन्डरले
श्री दिग्विजय सिमेन्ट कों. लि. कोयर और फेल्ट डिविजन
१४ नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-७०० ००१
ISI 8391-1977

माया

सर्वाधिक बिकने वाली समाचार पत्रिका

वर्ष ६०, अंक ७ १५ अप्रैल, १९८९

आवरण कथा

३०

यद्यपि अर्जुन सिंह अपने को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही कहते हैं और राजीव गांधी के नेतृत्व में अखंडित आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें जिन स्थितियों में मुख्यमंत्री-पद छोड़ना पड़ा है, उससे वे आहत-अपमानित हुए हैं। क्या अर्जुन सिंह इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई जवाबी हमले की योजना बना रहे हैं? अर्जुन सिंह की 'हिट लिस्ट' में कौन-कौन लोग हैं?

४९ बिहार

भागवत झा आजाद की जगह सत्येंद्र नारायण सिंह को गद्दी पर बिठाने से क्या इंका के विद्रोह पर अंकुश लग पायेगा?

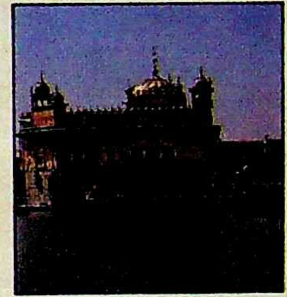

६९ पंजाब

पंजाब मसले को हल करने के लिए केंद्र ने जो नयी पहल की है, क्या वह कारगर सिद्ध होगी?

६६ तिब्बत

विफल विद्रोह की बीसवीं वर्षगांठ पर तिब्बत में माहौल ने जो उग्र रूप धारण किया है, उसको चीन काबू में कर पायेगा?

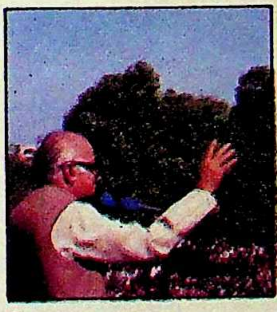

१७ भाजपा

क्या भाजपा फिर से 'जनसंघ' जैसा हिंदूवादी रूप अख्तियार करने जा रही है?

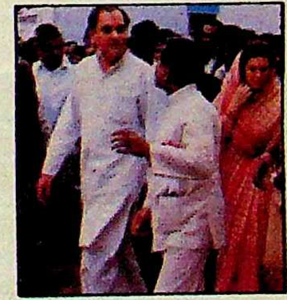

२६ राजीव अमेठी में

राजीव गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में हाल ही संपन्न 'विज्ञान प्रदर्शनी' की आड़ में कैसा खेल खेला गया?

९४ श्रीदेवी

अपने लाख टके के लटकों-झटकों की बदौलत अमिताभ की सी हैसियत कायम करनेवाली श्रीदेवी अब किस संकट में फंस गयी है?

दिल्ली दरबार : जो मेरा हाथ है, वह जगन्नाथ है! १०
खोजखबर : इफ्को आंवला परियोजना : भ्रष्टाचार का भांडा कैसे फूटा? २०
प्रसंगवश : हेगड़े बंबई की अदालत में क्यों गये? २४
अभिमत : भवानी सेनगुप्त : राजीव गांधी का कोई विकल्प नहीं ४३
मध्य प्रदेश : नये चेहरों को तरजीह ४६
हरियाणा : रघु यादव : एक बागी विधायक ४८
राजस्थान : इज्जत से खेलती राजनीति ५७
उत्तर प्रदेश : जसपुर कताई मिल में खूनी संघर्ष क्यों? ६०
उत्तर प्रदेश : मंत्रियों का यात्रा भत्ता ६३
घटनाक्रम : बड़ोदरा : अनाथों और विधवाओं का शहर ७६
खेल : प्रकाश पादुकोन ने संन्यास क्यों लिया? ७८
दूरदर्शन : धर्मयुद्ध : औद्योगिक घराने का महाभारत ८२
अर्थतंत्र : चुनावी वर्ष का हसीन धोखा ८५

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
ब्यूरो प्रमुख
बंबई : रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ : अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना : विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ : सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल : सुधीर सक्सेना
जयपुर : ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

० प्रधान कार्यालय : २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन : ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स : ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय : ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन : ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स : ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय : बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन : ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय : ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन : २६७४०, भोपाल कार्यालय : एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन : ६६३८८, बंबई कार्यालय : ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन : २४३५७७, तार : माया कहानी, टेलेक्स : ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन : २९९०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

आओ मिलकर हम 'घर-घर' खेलें !

Practical guide to
home landscaping
INTERIA 1987

जब जीवन भर की पूंजी लगायेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिये अपनी निशानी भी तो छोड़ कर जायेंगे।

जी हां! आखिर जीवन भर की पूंजी लगाकर जब अपना घर बनायेंगे तो किसी भी चीज़ में समझौते का सवाल ही नहीं उठता। खासकर सीमेन्ट का चुनाव तो बहुत ही सोच समझकर कीजियेगा।

फिर सबसे बेहतर सीमेन्ट की सही पहचान तो किसी अच्छे बिल्डर को ही हो सकती है, है ना? तो भारत के नं. 1 बिल्डर जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के वर्षों के अनुभव का फायदा अब आप भी उठाइये। जिस सीमेन्ट से वे बड़े-बड़े पुल और बांध देश-विदेश में बनाते हैं, उसी भरोसेमन्द सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट से आप भी अपना घर बनवाइये।

सीमेन्ट की क्वालिटी का मापदण्ड हमेशा उसमें उपयोग किये गये चूना-पत्थर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इसीलिये सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट का कारखाना देश के सबसे बेहतरीन चूना-पत्थर की खदानों में पास स्थित है। साथ ही साथ सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट अत्याधुनिक कम्प्यूटर युक्त तकनीक से बनाया जाता है।

तभी तो सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट में है बेजोड़ पकड़, लाजवाब मजबूती और बेमिसाल भरोसा।

जब भारत के नं. 1 बिल्डर के अनुभवों से बना सीमेन्ट उपलब्ध है, तो फिर भला किसी और सीमेन्ट को क्यों खरीदें?

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट : इसे नाम से मांगिये।

GUARANTEED QUALITY

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट की गारंटी
- तुरन्त मज़बूत पकड़
- 28 दिनों के बदले सिर्फ 3 दिनों में 330 kg/cm² की कम्प्रेसिव मज़बूती।
- हर बोरी में पूरा वज़न — पूरे 50 किलो।

मज़बूत रहे यह बंधन-जीवनभर

सुपरप्लस
जेपी
सीमेन्ट

मास्टर बिल्डर

जयप्रकाश इन्डस्ट्रीज़ का एक उत्कृष्ट उत्पादन

LINTAS (DELHI) JI 58 2621

धवन की वापसी
राजीव का
आत्मसमर्पण या
नयी किलेबंदी?

धवन की वापसी राजीव का आत्मसमर्पण या नयी किलेबंदी?

'माया' के ३१ मार्च, १९८९ के ताजा अंक का आवरण पृष्ठ एवं उस पर विषयों की विविधता को देखकर मैं 'माया' खरीदने का लोभ संवरण न कर पाया। सभी विषय एक से एक प्रासंगिक एवं मौजूं! आवरण कथा तो विशेष ही पसंद आयी, क्योंकि धवन के राजनीतिक मंच पर आने से राजनीति में जो परिवर्तन आया है, वह आश्चर्यजनक है। यह कथा पढ़कर मुझे 'माया' के उस अंक की याद आ गयी, जब 'माया' ने धवन पर ही कुछ महीने पहले 'सत्ता के शहंशाह कहां हैं' वाली आवरण कथा आयोजित की थी। मुझे तो यह भी लगता है कि 'माया' की ही धवन को लाने में परोक्ष भूमिका रही है। 'माया' ने धवन को लेकर जो सवाल उठाये हैं, उस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि धवन को पहले मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य समझने का मौका तो मिले। लेकिन जगन्नाथ मिश्र के आगमन से यह लगने लगा है कि कांग्रेस में अभी और परिवर्तन अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले हैं, क्योंकि धवन के जितने भी विश्वस्त लोग हैं, वे आंख गड़ाये बैठे हैं।—**अनिल विश्वास, ३६ एमआईजी, नागपुर**

राजीव का संकट

'राजीव का संकट' (१५ मार्च, १९८९) वाली रिपोर्ट वाकई विचारोत्तेजक लगी। यह संकट अब काफी गहरा गया है और कांग्रेस की साख निरंतर गिर रही है। हां, यह सच है कि राजीव गांधी के सलाहकारों ने अपनी सत्तालोलुपता एवं चाटुकारिता के कारण राजीवजी की छवि भी दूषित की है एवं कांग्रेस की लोकप्रियता भी घटी है जिसका फायदा विपक्ष निश्चित रूप से उठा रहा है। कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों ने ऐसी बगावत कर दी है जिसे ठीक-ठाक करने में बहुत समय लगेगा। राजीव गांधी की इज्जत को बचाने के लिए हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री एवं बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने आलाकमान के निर्देश पर इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के लिए हुए हंगामे को सुलझाने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन इससे कांग्रेस एवं राजीव का संकट हल होनेवाला नहीं है। जब उनके सलाहकार एवं मंत्री भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद में लिप्त रहेंगे, तो कांग्रेस की स्थिति बदतर होती ही जायेगी, जिसका परिणाम अगले आम चुनाव पर अवश्य पड़ेगा और विपक्ष अगर संगठित हो गया, तो इसका भरपूर लाभ भी उठायेगा।—**दीपक कुमार दीक्षित, जुडीशियल क्वार्टर, छज्जूबाग, पटना, बिहार**

जातीय झगड़ों का अखाड़ा

१५ मार्च के अंक में 'पंतनगर विश्वविद्यालय: जातीय झगड़ों का अखाड़ा' पढ़ा। इस रिपोर्ट में दी गयी जानकारियां बिलकुल सत्य हैं। जातिवाद और क्षेत्रवाद की जड़ें तो काफी समय पहले पड़ चुकी थीं। लेकिन इन जड़ों में पानी देने का काम मुख्यतः यहां होने वाले प्रत्येक कालेज की अपनी सोसाइटी और यूनियन के चुनाव हैं। विश्वविद्यालय में नये छात्रों के प्रवेश लेते ही क्षेत्रवाद, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले सीनियर्स इन्हें अपने ग्रुप में मिलाना शुरू कर देते हैं जोकि उनके लिए 'वोट बैंक' का काम करते हैं। नये छात्र ज्यादातर तो रैगिंग के भय से वैसे ही असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब उन्हें ऊपर से संरक्षण मिलता है, तो उनमें से ज्यादातर उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्रवाद, जातिवाद की जड़ें नये छात्रों में भी पनपने लगती हैं जो कि धीरे-धीरे मजबूत होती चली जाती हैं, जिसका विकराल रूप १९७८ के बाद उदयवीर सिंह की मृत्यु के रूप में हमारे सामने है। यहां की समस्याएं हल हो सकती हैं, यदि सोसाइटीज और यूनियन के चुनावों को कुछ समय तक बंद रखा जाये। विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति को हटाकर कोई नया कुलपति लाया जाये। रश्मि अग्रवाल कांड में दोषी दो मुख्य व्यक्तियों, उसकी एडवाइजर और डीन होम साइंस कालेज, जिन्हें विश्वविद्यालय में पुनः वापस ले लिया गया है, उन्हें हमेशा के लिए कैंपस से बाहर किया जाये।—**वीरेंद्र, छात्र, पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर**

फांसी पर ऐसे लटकाये जाते हैं लोग?

'माया' के १५ मार्च के अंक में 'फांसी पर ऐसे लटकाये जाते हैं लोग' शीर्षक के अंतर्गत रिपोर्ट पढ़कर दिल दहल गया। स्वयंभू खालिस्तान के कमांडों को अपने गिरेबान में झांक कर इस प्रश्न का उत्तर तलाश करना चाहिए कि निहत्थे और निरीह लोगों को स्टेनगनों के बल बूते पर फांसी पर लटका देना क्या बहादुरी और शौर्य का काम है। आठ-दस वर्ष से खून की नदियां बहाने के उपरांत भी क्या उन्हें 'खालिस्तान' मिल सका है?

विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर तथा उनकी स्वार्थसिद्धि का मोहरा बनकर क्या उग्रवादी अपना या देश का भला कर रहे हैं? यदि सरकार ने पंजाब के प्रति अपनी उदासीनता व निष्क्रियता का रवैया न बदला, तो मानवता अनंत काल तक कराहती रहेगी और भारत का इतिहास उसकी बेदर्दी, बेदिली व लापरवाही के लिए क्षमा नहीं करेगा।—**सुरेंद्र साह, लोदी रोड, नयी दिल्ली**

स्वामी को कथित दस्तावेज किसने दिया?

'माया' का नया अंक (मार्च १५, १९८९) मिला। इसमें 'स्वामी को कथित दस्तावेज किसने दिया?' पढा। स्वामी सुर्खियों में रहना शायद बहुत पसंद करते हैं, यह तो आये दिन समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में देखने को मिलता रहा है। मेरे खयाल में स्वामी इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। 'माया' के इस अंक में लिखा भी है कि स्वामी दूध के धोये नहीं हैं।—**मनोज कुमार शर्मा, बेगूसराय, बिहार**

आपका १५ मार्च का अंक देखने को मिला। बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वामी जैसे व्यक्ति को (जिनके बारे में यह कहावत चरितार्थ होती है—जहं-जहं पांव पड़े स्वामी के, तहं-तहं बंटाढार॥) कवरेज देकर अकारण महत्व दिया है।

कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, किंतु वे उतने ही विनम्र एवं शालीन भी होते हैं। कुछ लोगों को अपने बुद्धिमान होने का अहकार होता है। ऐसे ही लोग घर फूंककर तमाशा देखते हैं। श्री स्वामी इसी कोटि के जीव हैं। उनसे स्वच्छ राजनीति, देशहित, निष्ठा इन गुणों की अपेक्षा व्यर्थ है।—**सप्तर्षि, न्यू रोहतक रोड, नयी दिल्ली**

नौकरशाही: राजनीति के भंवर में

'माया' के १५ मार्च की विशेष रिपोर्ट 'नौकरशाही: राजनीति के भंवर जाल में' उन कारनामों का खुलासा करती है जो सत्ताधारियों के चंगुल में फंसे 'बेबस' सचिव गण करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सत्तानशीनों की पदलोलुपता बरकरार रखने में इनका जितना हाथ होता है, उतना ही सहयोग। नतीजतन राजनीति की चक्की में पिसना ही इनकी नियति बन गयी है।—**आलोक कुमार झा, खंजरपुर, भागलपुर**

इक्कीसवीं सदी आते-आते भारत दिवालिया हो जायेगा

माया, अंक १५ मार्च, डा० जय दुबाशी की निर्मम सत्य उद्घाटित करती रिपोर्ट 'सरकार कंगाल हो रही है' बेशक सच है। आज मुल्क पर लगभग दो लाख करोड़ रुपए कर्ज चढ़ चुका है, जो हमारे सारे उत्पादन का तिहाई है। सूद पटाने को भी कर्ज लेना पड़ रहा है। पंद्रह वर्षों के अंदर ही ब्याज कर्ज से ज्यादा होने वाला है। यहां भी पेरेस्त्रोइका की जरूरत है, लेकिन यह राजीव गांधी के बूते का नहीं, वे तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि कागजी मुद्रा छापकर कर्ज अदा कर दें, जिससे कीमतें इतनी बढ़ जायेंगी कि जनता त्राहि-त्राहि कर उठेगी, घिघिया उठेगी। यह गरीब मुल्क अगर सत्रह सौ करोड़ रुपए से एशियाड रचा कर अटारी पर धुवां कर

चिट्ठियां

सकता है, तो फिर हम इक्कीसवीं सदी की ओर ही तो बढ़ रहे हैं! सरकारी लाडलों का अनाप-शनाप अपव्यय देख इस देश पर तरस आता है। धन्नासेठों और खादीधारियों की तिजोरी कौन झांके? भारत के अर्थतंत्र की वस्तुस्थिति पर किससे कौन चर्चा करे? जो अधिकांश अर्थव्यवस्था किसान-मजदूर पर टिकी है, वह भी आसमानी-नागहानी, सुलतानी मार से पंगु हो चुकी है। संसार में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां जनता के साथ मुलाजिम इतना जुल्म करते हों। आसमानी योजनाओं पर जितना धन 'खर्च' किया जा रहा है, उससे तो एक नया हिंदुस्तान बसाया जा सकता है, लेकिन यहां तो बोफोर्स पचाने वाले बैठे हैं। कुरसी पर बैठते ही 'रंक' चलै सिर छत्र धराई'।सरकार कंगाल हो रही है? आखिर और हो भी क्या सकती है? देश बेच कर खा लेने वाले—देश को हांक रहे हैं! लेकिन जिस रफ्तार से देश चल रहा है, बारह-तेरह वर्षों बाद, इक्कीसवीं सदी आते-आते हर हाल में भारत दिवालिया हो जायेगा! **—प्रणय, लालगांव, रीवा, मप्र।**

बंबई पर दक्षिण की सिने महारानियों का वर्चस्व

'**मा**या' (१५ मार्च) के नवीनतम अंक में रवींद्र श्रीवास्तव का विचारोत्तेजक लेख 'बंबई पर दक्षिण की सिने महारानियों का वर्चस्व' बेहद पसंद आया। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि दक्षिण की अभिनेत्रियां ही हिंदी फिल्मों पर क्यों हावी हैं? वैसे देखा जाये, तो हम पायेंगे कि दक्षिण की प्रत्येक अभिनेत्री अपनी पहली ही फिल्म से अपनी एक छवि बना लेती है। यही कारण है कि श्रीदेवी की कई फिल्में पिटने के बावजूद वह आज भी 'नंबर वन' है, कारण उसकी ग्लैमरस छवि जो फिल्म 'हिम्मत वाला' से बन गयी थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्वाइंट यह है कि दक्षिण की नायिकाएं नृत्य में निपुण होती हैं, जबकि बंबई की नायिकाएं केवल सुंदरता का सहारा लेती हैं। यही कारण है कि दर्शक दक्षिण की नायिकाओं को पसंद करते हैं। **—हर्ष कुमार, ३६ देवपुरम, मुजफ्फरनगर, उप्र**

जातीय झगड़ों का अखाड़ा

पंतनगर विश्वविद्यालय से संबंधित, निशीथ जोशी की रिपोर्ट पढ़ी। कैसी विचित्र सी बात है कि एक विद्यार्थी की हत्या को लेकर बंद विश्वविद्यालय पर तो आपके लखनऊ संवाददाता ने एक विस्तृत रिपोर्ट कर दी, पर पंतनगर से ६५ किलोमीटर दूर स्थित कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल पर उन्होंने नजर नहीं डाली। कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में से सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली विश्वविद्यालय है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय योग्यता-विरोधी, प्रशासकीय दृष्टि से शून्य और सामान्य व्यवहार-शैली पर ऋणात्मक योग्यता रखने वाले व्यक्ति, श्री मुरलीधर के कुलपतित्व में लगातार दूसरी बार आया है।

श्री मुरलीधर अनेक वित्तीय अनियमितताओं के दोषी भी हैं, तथा मैं यह दावे के सात कह सकता हूं कि जातीयता/क्षेत्रीयता के वे सबसे बड़े पक्षधर हैं। डा० महातिम सिंह तो, मुरलीधर के सामने तृण-मात्र ही सिद्ध होंगे।

मैं 'माया' को आमंत्रित करता हूं कि वह कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति, श्री मुरलीधर के द्वारा की गयी वित्तीय, अकादमिक तथा प्रशासनिक अनियमितताओं पर विस्तृत लेख लिखे। **—रमेश चंद्र मिश्र, प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल**

खयालात

दिल्ली का खुशख्वाब देख रहे देवीलाल को मेरा चैलेंज है, अगर अगले आम चुनाव में उनकी पार्टी हरियाणा में दस सीटें भी ले ले, तो मैं 'पालिटिक्स' से संन्यास ले लूंगा। **—कृषिमंत्री भजनलाल, बीकानेर (पत्रकारों से बातचीत) में।**

उनसे (राजीव गांधी से) ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वे अपनी इस उम्र में तलफती धूलवाले गांवों और रेगिस्तान में अपनी बीवी के साथ ६०० किमी का सफर करेंगे, (दरअसल) वे पार्टी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। **—गुलाम नबी आजाद, 'इंडिया टुडे' में।**

मैं यह जरूर मानता हूं कि पिछले चार सालों में पेंचीदा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को मैं अच्छी तरह समझ सका हूं, लेकिन यह कत्तई नहीं समझ पाया हूं कि जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा क्या है? **—राजीव गांधी, संसद में।**

जानबूझ कर अनजान बनने वाले आदमी को या तो 'मूढ़' कहते हैं या 'धूर्त'। यदि वह (आदमी) प्रधानमंत्री हो तब उसे क्या कहा जाये? **—चंद्रशेखर, दिल्ली में।**

हम लगभग यह मान चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा तब तक चुनाव लड़ना बेतुका है जब तक हमारे पास, माकपा के समान, हथियारों का भंडार नहीं हो जाता। **—एबीए गनी खां चौधरी, कलकत्ता में।**

मैं जनतंत्र की उस परिभाषा को नहीं जानता जिसकी वे (तेलगूदेशम के विक्षुब्ध नेता) चर्चा करते हैं। **—एनटी रामाराव, हैदराबाद में।**

धार्मिक विषयों में राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है। **—कांची कामकोटि के शंकराचार्य, 'नवभारत टाइम्स' (रुश्दी प्रकरण) में।**

मैं महसूस करती हूं कि कट्टरपंथियों ने रुश्दी के धर्मद्रोह को बेहद फैला दिया है, जबकि उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। **—बेनजीर भुट्टो, बीबीसी से बातचीत में।**

मैं देश के सामने यह साबित कर देना चाहता था कि वफादारी क्या होती है। **—आरके धवन, इंडियन एक्सप्रेस में।**

हम खोजी पत्रकारिता का स्वागत करते हैं, पर कभी-कभी कुछ (पत्रकार) लोग इसकी जगह कल्पनापरक अथवा मनगढ़ंत पत्रकारिता भी करने लगते हैं। **—एचकेएल भगत, दिल्ली में।**

न्यायालय के विरुद्ध सब तरह के शब्द इस्तेमाल किये जा रहे हैं, यह महाभियोग से भी बुरा है। **—सुप्रीम कोर्ट के जज ई वेंकटरमैया, दिल्ली में (भोपाल मामले की न्यायपीठ से अलग करते हुए)।**

नौशाद साहब, ओपी नैयर या दूसरे संगीतकारों ने अपने सारे कैरियर में क्या उतनी फिल्मों की धुनें बनायी हैं जितनी मैंने चंद महीनों में? इस सचाई पर लोग हंगामा क्यों करते हैं? **—संगीत निदेशक बप्पी लाहिड़ी, बंबई में।**

बाल ठाकरे 'हिंदू अयातुल्ला खुमैनी' हैं। **—मुख्यमंत्री शरद पवार, बंबई में।**

शरद पवार महाराष्ट्र के अल्लाउद्दीन खिलजी हैं। अगर हम खुमैनी की तरह धर्मांध होते, तो पवार का सिर उड़ा देने का फरमान दे देते। **—बाल ठाकरे, पत्रकारों से वार्ता (बंबई) में।**

अगर एक पायलट एक राष्ट्र का संचालन कर सकता है, तो एक अभिनेता क्यों नहीं कर सकता? **—शत्रुघ्न सिन्हा, भोपाल में।**

गति दे

प्रीमा पर 106 शब्द प्रति मिनट की सुपर स्पीड. नैशनल स्पीड टाइपिंग चैम्पियनशिप में. हल्के स्पर्श का कमाल.

प्रीमा पर 123 घंटे लेगातार टाइपिंग. गिनिस बुक में शानदार स्थान. **प्रीमा** के टिकाऊ होने व बेशिकायत काम का प्रमाण.

प्रीमा में कितनी ही अनोखी विशेषताएं, जैसे पन्ना-समाप्त-सूचक और खड़ी-रेखा सुविधा. साथ ही 15 टाइपस्टाइल, ज्यादातर भारतीय और चुनी हुई विदेशी भाषाएं उपलब्ध.

प्रीमा के लिए देश-भर में फैला लाजवाब बिक्री-बाद-सेवा का जाल.

गोदरेज **प्रीमा.** भारत का नंबर एक टाइपराइटर. इसमें आश्चर्य कैसा !

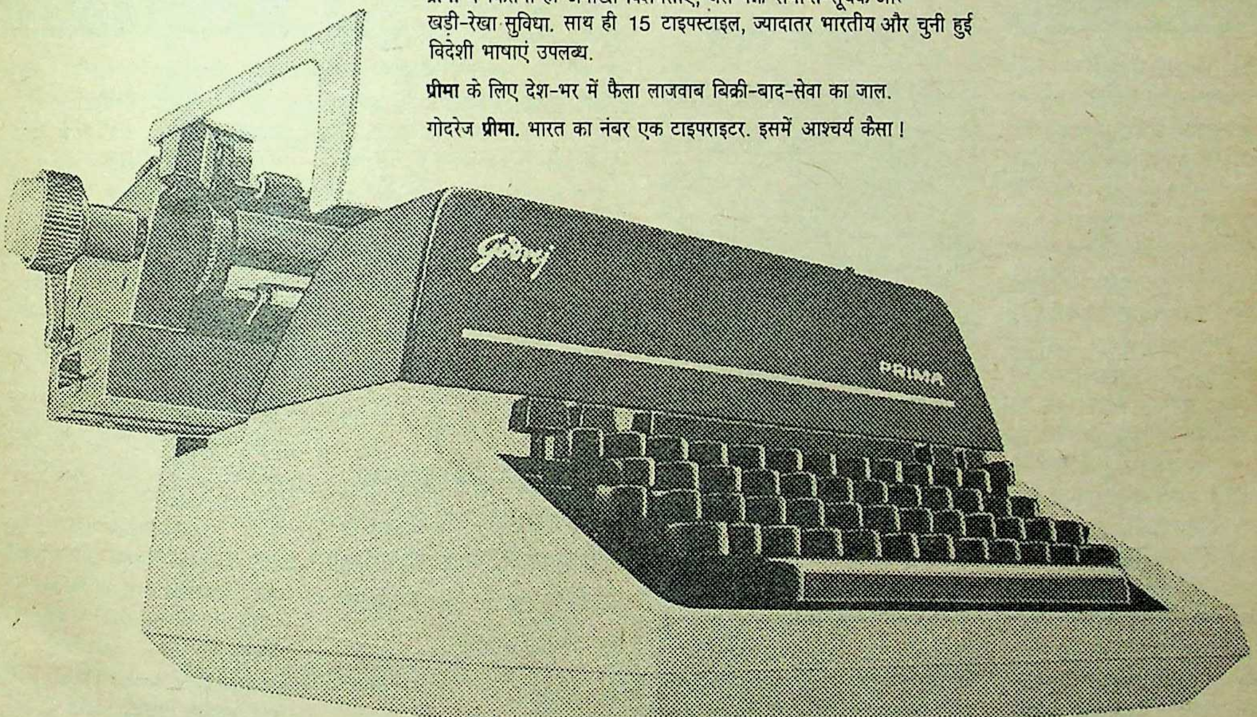

खूब चले

Godrej®

PRIMA

भारत का प्रमुख टाइपराइटर

ULKA-11755-HIN

धवन पर प्रहार

राजधानी दिल्ली में हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती। यह तो जगजाहिर है कि आरके धवन फिर से प्रधानमंत्री के समीप आ गये हैं और पार्टी को चुस्त-दुरुस्त बनाने में राजीव गांधी के सबसे विश्वास-पात्र सलाहकार हैं। किंतु जनता पार्टी सांसद सैयद शहाबुद्दीन भी तब अचंभे में पड़ गये, जब उन्होंने यह देखा कि धवन के संसद भवन स्थित कार्यालय से मुरली देवड़ा और दो अन्य कांग्रेसी सांसद बड़े सम्मान-जनक ढंग से बाहर निकले। शहाबुद्दीन के यह कहने पर कि वे तो बूटा सिंह से मिलने अगले कमरे में जा रहे हैं, इन सासंदों ने जवाब दिया, "आप जाइये बुझते हुए दिये से मिलने। हम तो उगते हुए सूरज के दर्शन करते हैं।" कुछ लोगों का कहना है कि न केवल मुरली देवड़ा, बल्कि कई केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी—जो कि धवन समर्थक नहीं कहे जाते-आजकल उगते हुए सूरज की सलामी बजा रहे हैं। एक कांग्रेसी सांसद का कहना था, "सूरज को देखकर ये लोग गायत्री मंत्र नहीं जपते, बल्कि जहर उगलते हैं और ऐसा बहुत दिनों तक चला, तो कहीं ग्रहण न लग जाये।" १४ मार्च को समभुच ऐसे आसार भी नजर आने लगे। उस दिन ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के कुछ अंश अचानक वितरित किये गये। श्रीमती गांधी की हत्या की जांच करनेवाले इस आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने 'देशहित' में उजागर नहीं किया है, लेकिन गुपचुप इसके अंशों का प्रकटीकरण काफी सनसनीखेज है। इन कथित अंशों में धवन की नीयत पर शक किया गया है। कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि ये अरुण नेहरू ने लीक किये हैं। अरुण नेहरू आंतरिक सुरक्षा राज्यमंत्री रहे हैं और बताया जाता है कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट की एक कापी उन्होंने अपने पास रख छोड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये अंश बूटा सिंह के सौजन्य से बाहर आये हैं। धवन के आने से बूटा सिंह की स्थिति कमजोर हुई है, इसलिए उन्होंने धवन को विवादों के घेरे में घेरा है। बहरहाल, धवन के आते ही सत्ता के संकरे गलियारे में धक्कामुक्की फिर शुरू हो गयी है।

गाडगिल की चिंता

इंका के दिल्ली स्थित २४ अकबर रोड मुख्यालय में गुलाम नबी आजाद की जगह वीएन गाडगिल को पार्टी का नया प्रवक्ता पिछले दिनों नियुक्त किया गया। इससे गुलाम नबी आजाद काफी दुखी हैं। उनको ऐसा लगता है कि उग्र कांग्रेस महाधिवेशन में राजीव गांधी की उपस्थिति में उन्होंने जिस सख्त भाषा का इस्तेमाल राज्य के कांग्रेसजनों के लिए किया था, उसी के परिणामस्वरूप उनको इस अधिकार से वंचित होना पड़ा है। उनको सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि राजीव गांधी ने उनसे बिना पूछे ही उनको अधिकृत प्रवक्ता की हैसियत से हटा दिया। लेकिन उनको उम्मीद है कि आनेवाले समय में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जायेगा।

दूसरी ओर पार्टी के नये प्रवक्ता गाडगिल पर तो सिर मुंडाते ही ओले पडे। उनको पार्टी प्रवक्ता बने अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि उन्होंने इंका मुख्यालय में शाम को पत्रकारों को बताया, "अभी बिहार की समस्या को हल करने में पांच-छह दिन लग जायेंगे।" जिस समय गाडगिल पत्रकारों को यह बता रहे थे, ठीक उसी समय पटना में भागवत झा आजाद राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को अपना मुख्यमंत्री पद से, पार्टी हाई कमान के निर्देश मिलने के बाद, इस्तीफा दे रहे थे।

जब उसी रात पत्रकारों ने गाडगिल को टेलीफोन पर पकड़ने की कोशिश की, तो बताया गया कि वे घर पर नहीं हैं। पत्रकारों ने दूसरे दिन उनको इंका मुख्यालय में पकड़ना चाहा, तो पता चला कि वे पुणे चले गये हैं। बताया जाता है कि गाडगिल ने इंका अध्यक्ष राजीव गांधी को रात में ही एक पत्र लिखा, "मुझे आपके कार्यालय से प्रेस को यह कहने के लिए फोन किया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री अभी पांच-छह दिन नहीं बदला जायेगा। लेकिन उसी समय पटना में मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे थे। इससे प्रेस के बीच मेरी विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मैं किस मुंह से प्रेस के सामने जाऊंगा।" जाहिर है, गाडगिल को चिंता होना उचित भी है, क्योंकि उन्हें जो महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है, उसमें उनको सही सूचना दी जानी निहायत जरूरी है। खैर, उन्होंने हाईकमान को पत्र तो लिख दिया है। अब देखना है कि वे प्रेस के बीच अपनी खोई प्रतिष्ठा कैसे बनाते हैं?

> **प्रेस के बीच मेरी विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मैं किस मुंह से प्रेस के सामने जाऊंगा।**

राजीव गांधी का विचित्र दौरा

११ मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के गौरीगंज की एक दिवसीय यात्रा पर आये राजीव गांधी अपने कार्यक्रमों से फारिग होने के बाद शाम लगभग ५ बजे उड़ान अकादमी पहुंचे। इस अकादमी के निदेशक बाबर पायलट प्रशिक्षण के दौरान राजीव गांधी के गुरु रह चुके हैं। वहां पहुंचकर राजीव गांधी ने अपने पायलट लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु सभी औपचारिकताएं पूरी कीं। टेस्टिंग देने के लिए उन्होंने २ घण्टे तक विमान उड़ाया। उनके साथ अकादमी के निदेशक बाबर भी थे।

राजीव गांधी का यह कार्य पूरी तरह व्यक्तिगत और गोपनीय रहा। गोपनीय इसलिए कि यह न तो पूर्वनिर्धारित था और न ही उनकी अगवानी में आगे-पीछे लगे सत्ताधारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी भनक थी।

चर्चा है कि राजीव गांधी का यह एक दिवसीय दौरा वास्तव में फिल्म निर्माता सिम्मी ग्रेवाल द्वारा उनके जीवन पर फिल्मायी जा रही आउटडोर शूटिंग के लिए आयोजित था। इस फिल्म में सिम्मी ग्रेवाल को जहाज उड़ाते हुए राजीव की पायलट जिंदगी को भी दर्शाना था। इसीलिए राजीव ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के बाद २ घंटे तक जहाज उड़ाकर सिम्मी ग्रेवाल का मंशा पूरा किया। उनके इस हवाई अभिनय में सिम्मी भी साथ थीं।

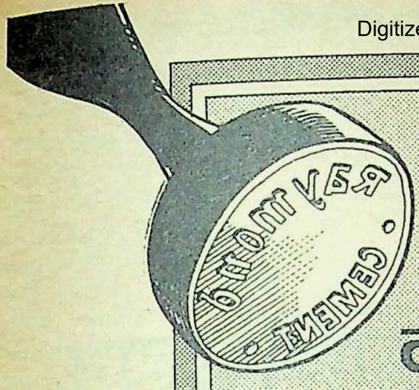

जब किसी निर्णय पर सालों-साल साथ निभाने की बात निर्भर हो तो ठोस प्रमाण उसमें मदद करते हैं

प्रमाण १ : गुणवत्ता
रेमण्ड का नाम ही सर्वोच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय है.

प्रमाण २ : मज़बूती
बी आइ एस के मानकों से निश्चय ही ज़्यादा 'कॉम्प्रेसिव' शक्ति.

प्रमाण ३ : ब्लेन
महीनतम ब्लेन के कारण अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मनचाही मज़बूती की गारंटी.

प्रमाण ४ : जमाव गुण
रेमण्ड सीमेंट पूर्ण जमाव का आश्वासन देता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव की अवधि बी आइ एस मानकों से बेहतर है.

प्रमाण ५ : विक्रेताओं का जाल
देशभर में रेमण्ड के अधिकृत विक्रेताओं का जाल शत प्रतिशत असली सीमेंट उपलब्ध कराता है.

प्रमाण ६ : पैकेजिंग
स्वचालित रोटरी पैकेजिंग मशीनों द्वारा सबसे मज़बूत प्लास्टिक और जूट की बोरियों में पैक याने निकाल लिए जाने का अंदेशा ही नहीं.

प्रमाण ७ : बचत
कोई अन्य सीमेंट हर बार इतने ठोस लाभों की गारंटी दे नहीं सकते.

प्रमाण ८ : हमारे कुछ ग्राहक
एन टी पी सी, ऑयल इंडिया लि., भारतीय रेलवे्ज़, वायजैक़ स्टील प्लांट, ईस्ट इंडिया होटल्स लि., आइ टी सी लिमिटेड, वोल्टास लि., टाटा रोबिन्स फ्रेसर, निटको टाइल्स, अंसल हाउसिंग प्रा. लि., एस.आर.एफ. निप्पॉन डेनरो इस्पात लि. जी.ई.सी.

कैलाश सीमेंट : निर्माता

रेमण्ड

गुणवत्ता का दूसरा नाम.

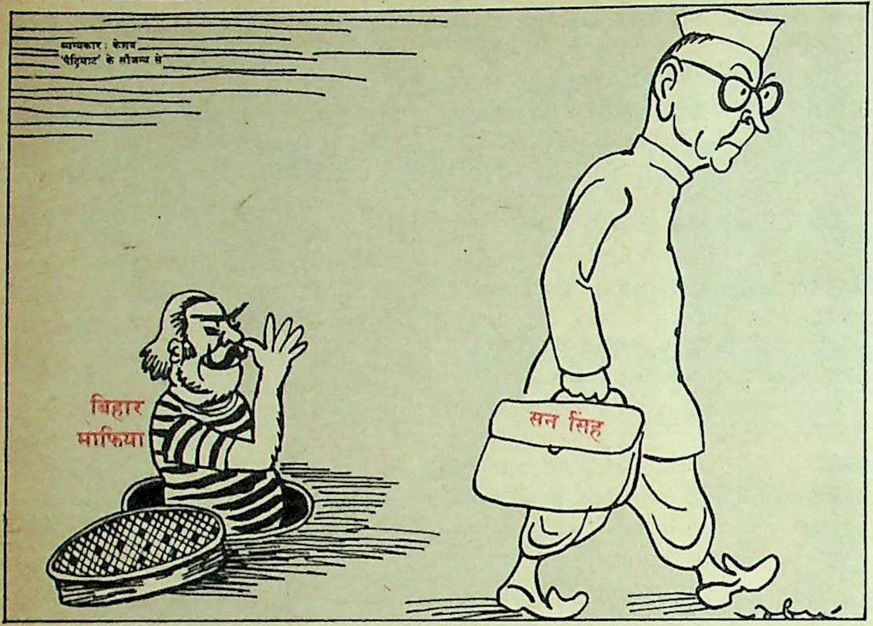

जो मेरा हाथ है, वह जगन्नाथ है !

आरके धवन ने 'प्रवेश' पाते ही कबाड़खाने से 'संकट मोचक छतरी' निकाल कर दिल्ली दरबार के चक्कर खा रहे सिर पर तान दी। छतरी के हैंडिल में बंधा ट्रांजिस्टर मस्ती में गाना गा रहा था—'सिर जो तेरा चकराये, या दिल डूबा जाये। आ जा प्यारे पास हमारे काहे घबराये...काहे घबराये...।' दरबार ने हाथ बढ़ाकर ट्रांजिस्टर के वाल्यूम को कम करते हुए पूछा, "आरके, इस बार छतरी को बुलेटप्रूफ तो करा लिया है न ?" धवन ने अदब से दरबार के सामने एयर इंडिया के महाराजा की तरह दोहरे होते हुए कहा, "सर, छतरी तो पहले से ही बुलेटप्रूफ थी। इस बार मैंने भी अपने को बुलेटप्रूफ कर लिया है। आप चिन्ता न करें। सामने से बुलेट आपकी बुलेटप्रूफ छाती झेलेगी। ऊपर से छतरी और पीछे से मेरी बुलेटप्रूफ पीठ। कहीं से कोई खतरा नहीं है।" धवन अपना वाक्य पूरा ही कर पाये थे कि दायें-बायें से सांय-सांय करके गोलियां आ गयीं। दरबार भयभीत हो उठा, "यह क्या ! आप कह रहे थे कि सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन दायें-बायें से हम पर बौछार हो रही है !" धवन ने संयत स्वर में कहा, "सर, पूरी तरह अगर मैं आपको 'एयर टाइट' कर दूंगा, तो दम घुट जाने का खतरा है। यह दायें-बायें से अपने ही बिहारी, राजस्थानी और गुजराती फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इनको 'टैकल' करने की जरूरत है।"

'टैकल' शब्द पर दरबार सहज होकर आगे बढ़ लिये, "एस, एस मिस्टर धवन। इनको टैकल करने की जरूरत है। हमने पहले यह काम अपने जिमनास्टिक क्लब की कप्तान शीला दीक्षित को सौंप रखा था। लेकिन वे 'टैकल' करने में मुक्केबाजी ज्यादा करती हैं। इसलिए उनसे यह काम लेकर आपको दिया गया है। फिलहाल आप बिहार को 'टैकल' करें। मैं पंजाब को टैकल करता हूं।" टहलते हुए दरबार अपने कांचघर के समीप आकर खड़े हो गये, "अच्छा तो मिस्टर धवन, अब मैं अपने कांचघर में पंजाब को 'टैकल' करता हूं। मुझे अब छतरी की यहां जरूरत नहीं। आप बिहार को टैकल करने के लिए जा सकते हैं।" दरबार कांचघर में घुस गये और धवन छतरी लेकर अपने साउथ ब्लाक के कक्ष में आ गये।

धवन के साउथ ब्लाक स्थित कक्ष में गहमागहमी थी। भीष्म नारायण सिंह दरबार से बतिया कर धवन को समझा रहे थे, "देखिए धवनजी। आप तो हमारे नेचर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं न। हम तो मिल-बांट कर चलने वाले आदमी हैं। आज बिहार की प्राब्लम यही है। आजादजी मिल-बांट कर नहीं न चले, इसीलिए विरोधियों ने उनके मुंह में कालिख पुतवा दिया। अरे नाम के आगे बड़ा-बड़ा 'आजाद' लिखवा देने से कोई आजाद नहीं न हो जाता है। आजाद होने के लिए दिल का आजाद होना जरूरी होता है न। देखिए न, यह हमारे जगन्नाथ बाबू हैं न। यह नाम से नहीं, दिल के आजाद हैं। इनको हमारे मुख्यमंत्री बनने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह दिल से आजाद हैं, भाई साहब।" पास सोफे पर बैठे जगन्नाथ मिश्र ने तपाक से अपना चश्मा उतार कर टेढ़ी नजर से देखा, "देखिए भीष्म बाबू ! आप धवनजी से अपना बात बोलिए। हमको दिल का आजाद कह कर आप अपना केस मजबूत करेंगे, तो हमारा केसवा तो पेंडिंग का पेंडिंग ही रह जायेगा न। हम आपको बोल दिये कि सिद्धांत रूप में हमको आपके मुख्यमंत्री बनने से आपत्ति नहीं है। लेकिन आप धवनजी को यह क्यों बोल रहे हैं कि हम आपका मुख्यमंत्री कैंडीडेचर सपोर्ट कर रहे हैं।" भीष्म बाबू चुप हो गये। धवन ने जगन्नाथ बाबू को इशारा किया कि वे अपना चश्मा पहन लें। जैसे ही उन्होंने चश्मा पहना, तो भीष्म बाबू फिर से शुरू हो गये, "देखिए धवनजी, बिहार की चीफ मिनिस्टरी में अब कुछ धरा नहीं है। पटने की गंगा में बहुत पानी बह चुका है न। अरे बिहार की चीफ मिनिस्टरी तो कांटे का ताज है। ठीक है जगन्नाथ बाबू के सिर पर रख दीजिए यह ताज। हम तो फिर से दरबार की 'वर्क्स-हाउसिंग' में आने के लिए तैयार हैं।" भीष्म बाबू गुमसुम होकर सोफे पर चिपक गये। इतने में लांग चढ़ाते हुए केसरीजी ने प्रवेश किया, "यह क्या धवनजी ! ब्राह्मण हटेगा, तो ठाकुर आयेगा और ठाकुर हटेगा, तो ब्राह्मण आयेगा। क्या बिहार में इन दोनों की ही बपौती चलेगी ? बिहार में क्या और कोई नहीं रहता है ?" केसरीजी ने घूर कर जगन्नाथ बाबू की तरफ देखा। जगन्नाथ बाबू भड़क उठे, "अरे केसरीजी, आप हमारी तरफ क्यों घूर कर देखे जा रहे हैं ? क्या हम पिछड़ों का हक मारे ले रहे हैं, अरे भीष्म बाबू की तरफ देखिए न ! जैसे ही सुने कि धवनजी बिहार को 'टैकल' कर रहे हैं, यह असम से आकर यहां गिरे हैं। अरे, हमको क्यों घूरे चले जा रहे हैं ? आप अगर और घूरेंगे न, तो देखिए केसरीजी, हमको भी अपना चश्मवा उतार देना होगा।" जगन्नाथ बाबू के चश्मा उतारने की धमकी से केसरीजी सहम गये और उन्होंने पैंतरा बदल लिया, "जगन्नाथ बाबू, आप एक बात समझ लीजिए

कि यह केसरी प्राण दे देगा, लेकिन कोई दरबार को ब्लैकमेल करे, बरदाश्त नहीं करेगा।" जगन्नाथ बाबू तमतमा कर सोफे से खड़े हो गये, "केसरीजी, अपना 'टंग' (जुवान) पर 'कंट्रोल' रखा जाये। देखिए हम दरबार को 'इनराइटिंग' दे चुके हैं कि 'बिहार विकास मंच' अब कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम अपना 'सपोरटर्स' के बोल दिये हैं कि अब 'प्रेसर टेक्टिस' बंद कर दीजिए, काम हो गया है। अब आप उस 'इस्यू' को 'रीओपन' करेंगे, तो ठीक नहीं होगा न।" केसरीजी ने जगन्नाथ बाबू की गरदन पर हाथ रख दिया, "बोलिए, आप लहटन चौधरी के मुख्यमंत्री 'कैंडीडेचर' को समर्थन देंगे?" जगन्नाथ बाबू हल्का-सा मुस्करा दिये, "केसरीजी पहले गरदन से हाथ नीचे किया जाये।" केसरीजी ने गरदन से हाथ हटाकर कंधे पर कर लिया, तो जगन्नाथ बाबू आहिस्ता से शुरू हुए, "केसरीजी, आप जगन्नाथ बाबू को गलत समझ रहे हैं। सिद्धान्त रूप में किसी बैकवर्ड को ही चीफ मिनिस्टर बनाने का समर्थक हूं। अगर लहटन चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो मेरा उनको पूरा नैतिक समर्थन है। मैं तो सिद्धांत रूप में किसी अल्पसंख्यक को ही मुख्यमंत्री बनाये जाने का समर्थक हूं।" केसरीजी ने कंधे से हाथ खींचकर अपनी नकली बत्तीसी भींच ली, "ठीक है। तुम लोग ऐसे नहीं न मानोगे। मुझे कोई केसरी चाल ही चलनी पड़ेगी।" केसरीजी ने पीछे हटकर ध्यान के लिए अपनी आंखें पलट लीं। थोड़ी देर ध्यानमग्न होकर वे चीख पड़े, "बिहार को टैकल करने के लिए केसरी फार्मूला लागू होगा।" धवन अपनी कुरसी से उठकर केसरीजी के पास आ गये। केसरीजी ने धवन के कान में फूंक मारी, "दरबार का आत्मविश्वास जगाना होगा। बिहार के सारे लोगों को अपना-अपना इस्तीफा दरबार को सौंप देना होगा।" जगन्नाथ बाबू तपाक से उठे—"मैं सिद्धांत रूप से इसका भी समर्थन करता हूं।" भीष्म बाबू इस्तीफे के नाम पर चौंक उठे। वे सोफे से उठकर बाहर जाने लगे, तो पीछे से केसरीजी ने उनको पकड़ लिया, "कहां खिसक रहे हो भीष्म बाबू। असम की गवर्नरी से इस्तीफा तो देते जाओ।" भीष्म बाबू ने केसरीजी से यह कह कर अपना पल्लू छुड़ा लिया, "देखिए केसरीजी, मैं राजनीति से फिलहाल उस समय तक परे हूं, जब तक गवर्नरी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं चलता हूं। मुझे कल अपनी गवर्नरी का अभिभाषण एक पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में पढ़ना है।" भीष्म बाबू लम्बे कदम बढ़ाकर भागने लगे, तो पीछे से जगन्नाथ बाबू ने ऊंचे स्वर में कहा, "अरे बाबू, आप घबरायें न। मैं सिद्धांत रूप में आपके मुख्यमंत्री कैंडीडेचर का पूरा समर्थन कर रहा हूं।"

दरबार कक्ष के बाहर 'लाल बत्ती' जल रही थी। अंदर धवन बिहार को 'टैकल' किये थे। धवन ने आईबी रिपोर्ट दरबार के सामने करते हुए कहा, "सर, वीपी सिंह के प्रभाव को बिहार में 'अंडरमाइन' नहीं किया जा सकता है किसी राजपूत को आजाद की जगह मुख्यमंत्री बना देने से वीपी सिंह का ग्राफ ७२ से गिरकर ३८ पर आ जायेगा। लेकिन वह राजपूत दबंग होना चाहिए।" पीछे से जगन्नाथ बाबू मिनमिनाये, "श्रीमन्, मैं सिद्धांत रूप में इस प्रस्ताव से सहमत हूं।" दरबार ने एक नजर उठाकर जगन्नाथ बाबू की तरफ देखा, उसके बाद आईबी रिपोर्ट पर फिर से निगाह गड़ा दी। धवन ने आगे फुसफुसा कर कहा कि जगन्नाथ मिश्र को प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष बनाने पर करीब-करीब सारे लोग सिद्धांत रूप में सहमत हैं।" जगन्नाथ बाबू ने दूर खड़े-खड़े बिना कुछ सुने कहा, "सर, मैं इस प्रस्ताव पर भी सिद्धांत रूप से सहमत हूं।" दरबार ने फिर जगन्नाथ बाबू की तरफ देखा। मुस्करा कर फिर रिपोर्ट पर आंखें गड़ा लीं। धवन ने पन्ना पल्टा, "सर, सत्येंद्र नारायण सिंह इधर फिर पाला पलटने की फिराक में हैं। राजा मांडा से उनकी बातचीत चल रही है। उनकी बीवी किशोरी सिंह लगातार वीपी सिंह की बीवी सीता सिंह की तारीफ़ करती हुई पायी जाती हैं। अगर सत्येंद्र बाबू को मुख्यमंत्री बना दिया जाये, तो...।" जगन्नाथ बाबू बीच में फिर टपक पड़े, "हुजूर, मैं सिद्धांत रूप में सहमत हूं...।"

> **जगन्नाथ बाबू ने भजनलाल से कहा, "जरा करीब आ जायें, तो बताऊं। भजनलालजी, यह जो मेरा हाथ है, वह जगन्नाथ है। मेरा हाथ, जगन्नाथ।" दरबार किसी ऊहापोह में फंसें कि धवन ने तुरन्त 'संकट मोचक छतरी' उनके चक्कर खा रहे सिर पर तान दी। छतरी के हैंडिल में बंधा ट्रांजिस्टर मस्ती में गाना गा रहा था—"सिर जो तेरा चकराये या दिल डूबा जाये...।"**

राजेन्द्रीजी ने भी आगे बढ़कर सुझाव दिया, "श्रीमन्, हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा वीपी सिंह का ही है। एक बार इस खतरे से निबट लिया जाये, तो सारे और खतरे गौण हो जायेंगे।" दरबार ने सामने से वह फाइल हटाकर पुरानी फाइल खोल ली। राजेन्द्रीजी ने आगे कहा, "देश की राजनीति में महत्व तो ठाकुर और ब्राह्मणों का ही है, जब तक देश में पूरी तरह द्रमुक न छा जाये। वीपी सिंह के अजगर से 'र' यानी राजपूत किसी तरह निकाल लिया जाये, तो देवीलाल के पास केवल 'अजग' रह जायेगा। सर, यह अजग (अहीर, जाट, गूजर) हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।" जगन्नाथ बाबू का स्वर फिर से उभरा, "मैं सिद्धांत रूप में इस सुझाव...।" दरबार ने राजपूत मुख्यमंत्री बनाये जाने के पन्ने पर जैसे ही हाथ रखा, भीड़ को चीरते हुए सत्येंद्र बाबू अपनी सांसद बीवी किशोरी सिंह को लेकर आगे आ गये, "अगर भीष्म बाबू मुझसे दमदार ठाकुर हों, तो उनको जरूर मुख्यमंत्री बनायें। मैं वीपी सिंह के साथ मिलकर दिखा दूंगा कि कौन असली राजपूत है।" जगन्नाथ बाबू ने आगे बढ़कर सत्येंद्र बाबू को पकड़ लिया, "मैं सिद्धांत रूप में आपके साथ हूं।" जगन्नाथ बाबू उनको लेकर पीछे आये, तो बिंदेश्वरी दुबे ने बढ़कर अय्यर आयोग की रिपोर्ट दरबार के सामने रख दी, "सर, मैं तो गवर्नरी पर जा ही रहा हूं। लेकिन जाते-जाते जरा सत्येंद्र बाबू के कारनामे दिखाता जाऊं। जब वे ६१ से ६७ तक बिहार में मंत्री थे, तो इस आयोग ने जांच करके पांच मामलों में से दो मामलों में उनको दोषी पाया था।" दरबार ने अय्यर कमीशन की रिपोर्ट दुबेजी से लेते हुए कहा, "अच्छा, यह तो मुझे मालूम नहीं था।" दरबार ने घूमकर जार्ज से कहा कि २४, अकबर रोड पर विट्ठल गाडगिल को फोन करके कह दो कि अभी पांच-सात दिन बिहार टैकल करने में और लगेंगे।" जार्ज गाडगिल साहब को फोन करने के लिए तुरन्त कक्ष के बाहर चले गये। इतने में भजनलाल ने 'फ्लोर' संभाल लिया, "सर, हमाम में हम सब नंगे हैं। अगर आप इन कमीशनों के चक्कर में पड़ गये, तो 'अजगर' लेकर देवीलाल हम लोगों के दरबार में घुस आयेगा। धवत्तजी आप पटना भागवत झा आजाद को फोन करें की वे तुरन्त पहाड़िया (गवर्नर) को अपना इस्तीफा दें। कल हम लोग जाकर सत्येंद्र बाबू को मुख्यमंत्री की कुरसी पर बिठा कर आते हैं।" दरबार ने धवन की तरफ देखा। लेकिन इसी के बीच जगन्नाथ बाबू ऊंचे स्वर में बोल उठे, "मैं इस प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में समर्थन करता हूं।" धवन ने तुरन्त आजादजी को इस्तीफा देने के लिए फोन मिलाया, तो भजनलालजी ने जगन्नाथ बाबू से पूछा, "आप हर बात का सिद्धांत रूप में समर्थन क्यों करते हैं?" जगन्नाथ बाबू ने भजनलाल से कहा, "जरा करीब आ जायें, तो बताऊं। भजनलालजी, यह जो मेरा हाथ है, वह जगन्नाथ है। मेरा हाथ, जगन्नाथ।" दरबार किसी ऊहापोह में फंसें कि धवन ने तुरन्त 'संकट मोचक छतरी' उनके चक्कर खा रहे सिर पर तान दी। छतरी के हैंडिल में बंधा ट्रांजिस्टर मस्ती में गाना गा रहा था—"सिर जो तेरा चकराये या दिल डूबा जाये...।"

—दरबारी लाल

देश

१ मार्च : विपक्ष द्वारा लोकसभा में न बैठने का निर्णय वापस। रुश्दी की पुस्तक के विरोध में श्रीनगर में तीसरे दिन हिंसा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल का निधन।

२ मार्च : जेएन दीक्षित पाकिस्तान में भारत के नये राजदूत। अरुणांचल प्रदेश के एक गांव में असम पुलिस के जवानों ने १० घर फूंके।

३ मार्च : अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल वकील की प्रधानमंत्री राजीव गांधी से नवीनतम अफगान स्थिति पर संक्षिप्त वार्ता, भारत द्वारा अफगानिस्तान को खाद्यान्न सहायता का वायदा। जमशेदपुर स्थित टिस्को (टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी) के एक पंडाल में आग लगने से कई मरे।

४ मार्च : बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद तथा बिहार के सात केंद्रीय मंत्रियों का अपने पदों से त्यागपत्र। दिल्ली में नेहरू शताब्दी दौड़ में लगभग ढाई लाख लोग शामिल थे।

५ मार्च : बड़ोदरा में जहरीली शराब पीकर ८७ मरे, ३५ नाजुक स्थिति में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा गदर पार्टी के संस्थापक बाबा पृथ्वी सिह आजाद का निधन।

६ मार्च : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कस्टम अधिकारियों द्वारा हड़ताल। बिहार में २० तीर्थयात्री गुफा में दम घुटने से मरे।

७ मार्च : 'एक्सप्रेस ग्रुप' के तीन कार्यालयों पर आयकर छापे।

८ मार्च : हेगड़े का डा० स्वामी पर २ करोड़ रुपए मानहानि का दावा। लोकसभा में इंका सांसद वैजयंती माला बाली द्वारा नेहरू शताब्दी दौड़ की आलोचना।

९ मार्च : यूरोपीय आर्थिक समुदाय में जीवी राम कृष्ण भारत के नये राजदूत नियुक्त।

१० मार्च : बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद का इस्तीफा स्वीकृत, नये मुख्यमंत्री के चयन हेतु कांग्रेस विधायक दल की बैठक। अभिनेत्री शबाना आजमी तथा आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश की सांप्रदायिकता के विरोध में दिल्ली से मेरठ तक की चार दिवसीय यात्रा शुरू।

११ मार्च : सत्येंद्र नारायण सिह बिहार के नये मुख्यमंत्री बने। छठवीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल।

१२ मार्च : नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीयों के लिए पहचान पत्र जरूरी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सिमी ग्रेवाल की दूरदर्शन फिल्म निर्माण प्रारंभ। १९८७ के ज्ञानपीठ पुरस्कार से मराठी कवि एवं नाटक लेखक वीवी शिरवाड़कर उर्फ कुसुमाग्रज सम्मानित।

१३ मार्च : बोम्मई मंत्रिमंडल का विस्तार, नौ और मंत्री शामिल।

१४ मार्च : अकाली दल के तीन गुटों की एकता का प्रयास विफल। सी राजेश्वर राव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पुनः महासचिव बने।

१५ मार्च : विपक्ष द्वारा ठक्कर आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश करने का आग्रह, सरकार द्वारा इनकार। हंगामे तथा दुर्व्यवहार के कारण ६३ विपक्षी लोकसभा सदस्य निलंबित।

वसंत दावा पाटील

बड़ोदरा में शराब का कहर

सत्येंद्र नारायण सिंह

सलमान रुश्दी

विदेश

१ मार्च : अमरीकी नौसेना का सातवां बेड़ा सात हजार सैनिकों सहित करांची बंदरगाह पहुंचा। ईरान में अंतरराष्ट्रीय तस्करी के लिए दो महिलाओं सहित ५० को फांसी।

२ मार्च : अमरीका ने रुश्दी से संबंधित सोवियत प्रस्ताव ठुकराया, इंग्लैंड ने रुश्दी की पुस्तक पर वार्ता का ईरानी प्रस्ताव ठुकराया, ईरान के धार्मिक नेता खुमैनी को समर्थन देने के कारण स्वीटजरलैंड का पत्रकार समाचार-पत्र से बाहर।

३ मार्च : दीनगिरि बन्दा विजय तुंगे श्रीलंका के नये प्रधानमंत्री बने।

४ मार्च : रुमानिया में मानवाधिकार हनन की जांच हेतु हंगरी का संयुक्त राष्ट्र से निवेदन। मारीशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ पर हमले का विफल प्रयास।

५ मार्च : शांति सेना की कार्रवाई में ५० लिट्टे कार्यकर्ता मरे।

६ मार्च : तिब्बत में हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का इस्रायली प्रधानमंत्री इसहाक शमीर से वार्ता का प्रस्ताव।

७ मार्च : ल्हासा में मार्शल ला। जलालाबाद पर नियंत्रण के लिए अफगान सैनिकों तथा विद्रोहियों में भीषण संघर्ष। ईरान ने ब्रिटेन से कूटनीतिक संबंध तोड़े।

८ मार्च : जलालाबाद पर बागियों का आक्रमण विफल, काबुल हवाई अड्डे पर राकेट वर्षा। सभी विदेशी पर्यटकों को ल्हासा छोड़ने का आदेश।

९ मार्च : बुश नें रक्षामंत्री पद हेतु जान टावर का नामंकन वापस लिया। रुश्दी की हत्या के उद्देश्य से निकली एक महिला सहित दो ईरानी गिरफ्तार।

१० मार्च : पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी सहायता में कोई कटौती न करने की अमरीकी घोषणा।

११ मार्च : रिचर्ड चेनी अमरीका के नये रक्षामंत्री मनोनीत।

१२ मार्च : बेनजीर भुट्टो का सत्ता का १०० वां दिन। फिलीपींस में कम्यूनिस्टों से संघर्ष।

१३ मार्च : अमरीका द्वारा पश्चिम एशिया में शांति हेतु कदम उठाने का निश्चय। रुश्दी को खुमैनी द्वारा प्रस्तावित सजा पर इस्लामी सम्मेलन संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से एक दिन पहले शिया-सुन्नी संप्रदायों में तीव्र मतभेद।

१४ मार्च : दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रपति पीटर बोथा को हटाने तथा एफ डब्ल्यू क्लेर्क को नया राष्ट्रपति बनाने का समर्थन। अफगान मुजाहिदीनों से अमरीकी स्ट्रिंगर मिसाइल वापस लेने का सीआईए का निर्णय।

१५ मार्च : बेरूत में युद्धविराम लागू। ज़ापान में विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नोबोरू ताकेशिता के त्यागपत्र की मांग। जापान के समुद्र में रसायन टैंकर में भीषण आग। पेरू की २३ वर्षीया श्रीमती लुसिला बोगियानो द जेगर को विश्व सुंदरी का खिताब। सलमान रुश्दी की विवादास्पद पुस्तक 'द सेटेनिक वर्सेज' के प्रकाशन पर इंडोनेशिया द्वारा प्रतिबंध। ब्रिटेन द्वारा बेरूत स्थित अपने वाणिज्य एवं वीसा कार्यालय बंद करने की घोषणा।

जाहिर है, कोई आपको मोटा या 'बेचारा मोटा' कहकर अपने साथी से बात करे, तो आपको थोड़ा बहुत दुख होगा और आप अपमानित महसूस करेंगे। निस्संदेह मोटापा जिंदादिली कम कर देता है, किंतु यह धारणा विकसित करना कि अत्यधिक तंदुरुस्त हो गये लोग किसी काम के नहीं रह जाते यह किसी हद तक तो गलत है ही। सुडौल शरीर रखनेवाली जनता से मुकाबला करने के उद्देश्य से अमरीका की मोटी महिलाओं ने 'मोटापे को सौंदर्य' का पर्याय बताने का अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान को गति देने के लिए इन महिलाओं ने 'नेशनल एसोसिएशन टू एड फैट अमरीकंस' नामक संगठन बना लिया है। इस संगठन में नर्तकियों की एक टोली है जिसे 'फातिमा' के नाम से जाना जाता है। इनका काम तरह-तरह के नृत्य करके सिर्फ यह बताना है कि मोटापे से जिंदादिली या उत्साह में कमी नहीं आती और मोटे लोग पृथ्वी पर बोझ नहीं हैं। एक अनुमान के अनुसार ३८० लाख अमरीकी पुरुष तथा महिलाएं औसत से ज्यादा वजन की हैं तथा मोटापे के कारण उनके शरीर ऐसे हो गये हैं कि देखकर लोग ताज्जुब करते हैं। फिर यदि इन लोगों को कोई खाते-पीते देख ले, तो और ताज्जुब में पड़ जायेगा, क्योंकि इन्हें 'डाइट' आदि के सिद्धांतों से कुछ लेना-देना नहीं। बहुतेरी अमरीकी औरतों का वजन तो २०० पाउंड से भी अधिक है, किंतु उन्हें अपने शरीर पर नाज है। तभी वे तरह-तरह की भड़कीली पोशाकें पहनकर अंग प्रदर्शन करती हैं।

पदयात्राओं का मुकाबला दौड़ों से करने का जो नायाब रास्ता प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा उनके सहयोगी ने ईजाद किया है, उसी पर अमल करते हुए उनके नाना पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म शताब्दी समारोह वर्ष के दौरान, ४ मार्च को दिल्ली में नेहरू शताब्दी दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमेच्योर एथलीट फेडरेशन आफ इंडिया के सहयोग से पुणे इंटरनेशनल मैराथन ट्रस्ट ने ४२ किलोमीटर लंबी 'इनकैब दिल्ली इंटरनेशनल मैराथन' का आयोजन भी किया था, जिसमें लगभग दस देशों के धावकों ने भाग लिया। ईनामी मैराथन दौड़ की पुरुष वर्ग की बाजी ब्रिटेन के टोनी साइमंस के हाथ लगी, जिन्होंने २ घंटा २४ मिनट ४२ सेकेंड में दौड़ पूरी की और महिला वर्ग का खिताब सुमन मेहता ने हासिल किया। ईनामी मैराथन के बाद शुरू हुई नेहरू शताब्दी दौड़, जिसमें सफेद ट्रैकसूट पहने प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों सहित लगभग ढाई लाख लोगों ने भाग लिया।

हालांकि इस आयोजन की नेहरू समर्थकों ने आलोचना की है, क्योंकि उनका मानना है कि नेहरू जैसी शख्सीयत को याद करने के लिए गंभीर बहस-मुबाहिसों जैसे सम्मानजनक समारोहों का आयोजन होना चाहिए था। यही नहीं, ८ मार्च को लोकसभा में इंका सांसद वैजयंतीमाला बाली ने यह आरोप लगाया कि नेहरू शताब्दी दौड़ में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गयी। साथ ही उन्होंने इस आयोजन पर अनावश्यक रुपए बहाये जाने की आलोचना की। ऐसी दौड़ जैसे हास्यास्पद आयोजनों पर अनावश्यक रूप से लोकधन सर्फ करके और उसमें महिलाओं से छेड़छाड़ का शोहदों को मौका देकर नेहरू का नाम और संदेश रौशन हुआ है या धूमिल—सोचिए जरा!

छाया : सुनील सक्सेना

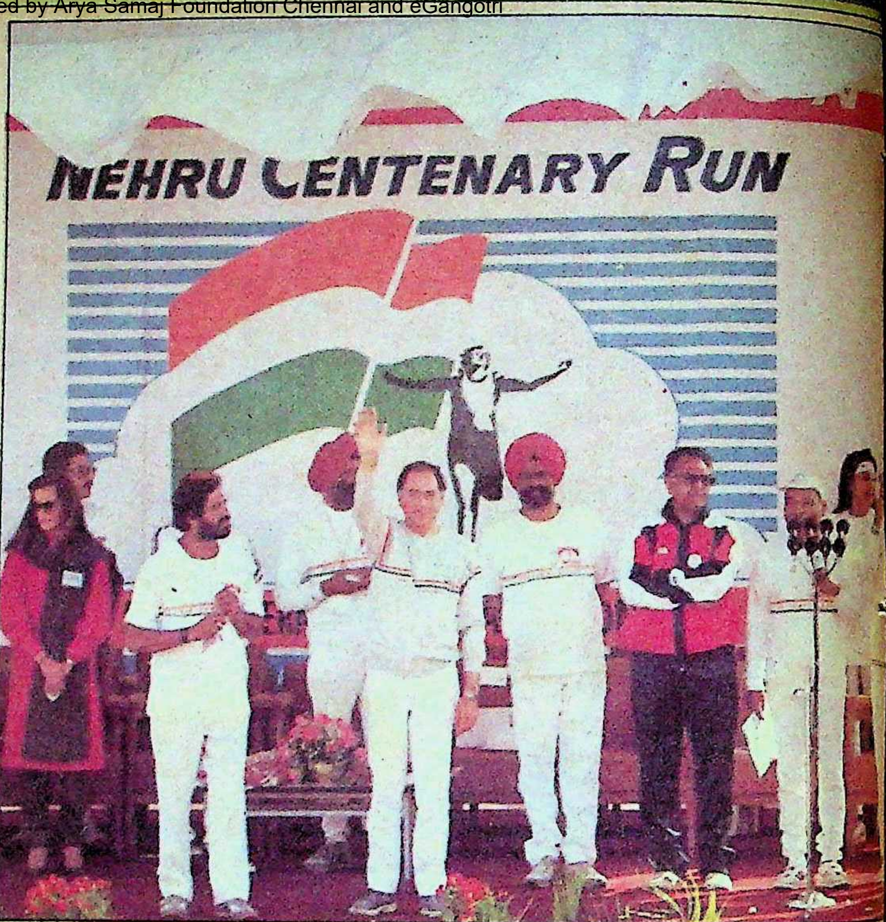

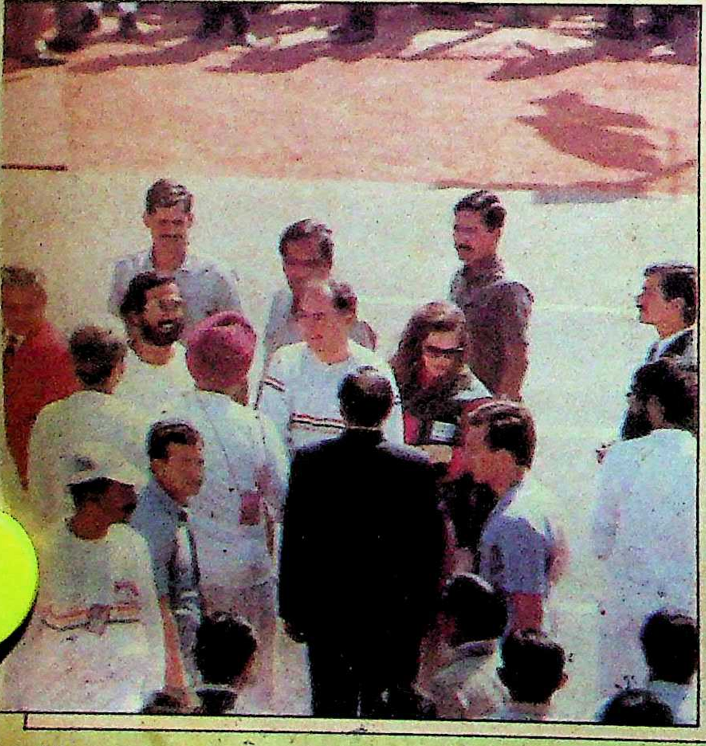

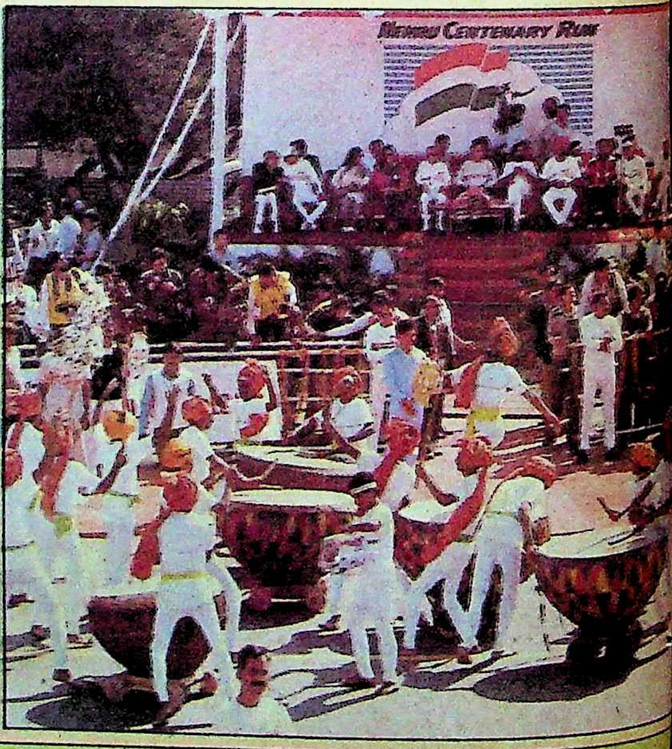

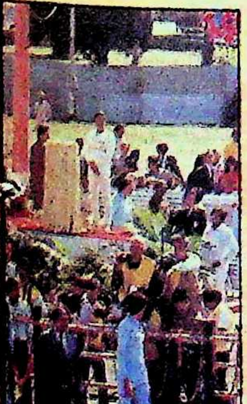

NEHRU CENTENARY RUN

छाया :
मनमोहन शर्मा

'३३ वर्षीय, जायसवाल, १६० सेमी, स्नातकोत्तर, संगीत प्रवक्ता, मासिक आय २५०० रुपए, आकर्षक व्यक्तित्व, किंतु दृष्टिहीन वर हेतु कन्या चाहिए। जाति बंधन नहीं।' इस विज्ञापन की परिणति एक ऐसे आदर्श में हुई है, जो रूप और रुपयों के तराज़ू पर वर-वधू को तौलनेवाले समाज के लिए आलोक स्तंभ बन सकता है। इस विज्ञापन को दांपत्य का सेतु बनानेवाली कोई सामान्य युवती नहीं है, बल्कि वकील से मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनी रंजना सक्सेना हैं। विज्ञापित वर को उन्होंने किसी सहानुभूतिवश नहीं, सहज स्नेहवश और ज़िंदादिली से चुना है। वर भी ऐसी वधू को पाकर कृतज्ञ नहीं, गौरवान्वित है। इसी सहस्वीकृति के कारण १२ फरवरी '८९ को रंजना सक्सेना और नेत्रहीन सतीश जायसवाल लखनऊ में आर्य समाज के रीति रिवाजों के अनुसार परिणय-सूत्रों में बंध गये। इस अवसर पर दोनों पक्ष के लोग उपस्थित रहे। लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत की शिक्षा प्राप्त और अंग्रेजी से एमए सतीश जायसवाल संप्रति भारतीय बालिका विद्यालय में संगीत के प्रवक्ता हैं। ग़ोरखपुर के वी सहाय की सुपुत्री रंजना पहले पेशे से वकील होने के कारण अन्याय के खिलाफ लड़ती रही थीं, लेकिन अब वे न्याय देने की कुरसी पर विराजमान हैं।

दुविधा का दौर: दिल्ली सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता

छाया: गिरीश श्रीवास्तव

भाजपा का आत्ममंथन

भाजपा पुनः आत्ममंथन की स्थिति में है। समस्या १९७७ पूर्व की हिंदुत्व की अपनी जनसंघ-छवि को पुनः ग्रहण करने अथवा वर्तमान उदारवादी नीति-रीति बनाये रख जनता दल से चुनावी तालमेल कर लोकसभा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की है। प्रश्न यह है कि उसकी वर्तमान रणनीति की विवशताएं और अनिवार्यताएं क्या हैं? क्या वर्तमान धर्मसंकट से निकल वह अपनी 'मूल्य पर आधारित' राजनीति में कामयाब होगी? अथवा समूचे विपक्ष से अलग-थलग हो अपना अलग राग अलापने को विवश होगी?

जुलाई, १९८८ की जमशेपुर में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बहस पार्टी की भावी रीति-नीति पर गंभीर रूप धारण कर रही थी। एक प्रतिनिधि का सुझाव आया कि भाजपा अपने खोये जनाधार और प्रतिष्ठा के लिए हिंदुत्व की भावना से पुनः जुड़े। एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार यह सुन पार्टी के शीर्षस्थ नेता अटल बिहारी वाजपेयी यकायक तीव्र कटाक्ष कर बैठे, "पुराने समय और पुरानी भावनाओं को जगाने के प्रयास में ही हम १९५२ की उस स्थिति में जा पहुंचे हैं, जब लोकसभा में हमारे पास मात्र दो सदस्य थे।"

आत्मविश्वास: दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीन दिवसीय (३ से ५ मार्च) बैठक में कहा, "मुझे हिंदू होने का गर्व है। हिंदू होकर मैं पूरे ब्रह्मांड से जुड़ता हूं, जबकि भारतीय होकर तो केवल इस दुनिया से ही जुड़ पाता हूं।" वाजपेयी के विचारों में आये इस भारी अंतर का एक कारण कदाचित यह हो सकता है कि गत दिनों उनके उदारवादी रुख को लेकर अफवाहों का बाजार बेहद गर्म रहा है। किंतु भाजपा की विवशता निश्चित रूप से विपक्षी एकता की बढ़ती संभावनाओं में अलग-थलग पड़ जाने का दरपेश खतरा रही है। इसके अतिरिक्त भाजपा अपने पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को हर हाल में खुश रखना चाहती है, ताकि उसका जनाधार मजबूत हो सके और चुनाव के समय मोल-भाव करने के लिए स्थिति मजबूत हो सके।

उदयपुर की बैठक में भाजपा ने न केवल हिंदुत्व का बाना ही ऐलानिया ओढ़ा, बल्कि अपने बुलंद हौसलों के चलते यह भी घोषणा की कि आगामी चुनावों में दूसरे विपक्षी दलों से सीटों का समुचित और सम्मानजनक तालमेल न होने की स्थिति में, उसमें अकेले चलने की भरपूर सामर्थ्य है।

भाजपा के इस बढ़े आत्मविश्वास पर टिप्पणी करते हुए एक वरिष्ठ विपक्षी सांसद ने 'माया' से कहा, "जब भोज के निमंत्रण के न आने की आशंका हो, तो पहले से ही उसमें नहीं जाने की जोर-शोर से घोषणा करना अस्वाभाविक नहीं। तालमेल के प्रश्न पर भाजपा ने जिस प्रकार सभी विकल्प खुले रखे हैं, वह उसकी अनिश्चितता व 'मन मन भाये मुड़िया (सर) हिलाये' की मनोदशा का स्पष्ट द्योतक है।"

ठीक विपरीत राय भाजपा महासचिव जगदीश प्रसाद माथुर की है। उनके अनुसार, "विकल्प खुला रखना हमारी अनिश्चितता की निशानी नहीं, हमारे लक्ष्य—राजीव हटाओ—और नीति—साथ नहीं तो 'एकला चलो'—बहुत स्पष्ट हैं।"

भाजपा के बदले रवैये और ताजा निर्णयों के तीन प्रमुख कारण हैं: सर्वप्रथम, जनता दल का अंतर्कलह, जिससे एक ओर उसकी एकजुटता कम हुई है, तो दूसरी ओर जनता के बीच उसकी साख भी गिरी है। इस स्थिति के कारण जनता दल से हटनेवाले जन-समर्थन को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास कार्यकर्ताप्रधान अनुशासित पार्टी भाजपा ने किया है। दूसरे, उत्तर प्रदेश के हाल के स्थानीय चुनावों में भाजपा को प्राप्त सफलता जो उसके लिए संजीवनी सिद्ध हुई है। तीसरे शिवसेना से भाजपा की बातचीत और समझौते की संभावना।

भाजपा अध्यक्ष आडवाणी के अनुसार, "पार्टी में व्याप्त वर्तमान आत्मविश्वास गत वर्ष के आगरा पार्टी अधिवेशन में अपनायी गयी रणनीति और उस पर अमल का प्रत्यक्ष नतीजा है। वहां हमने शिखर राजनीति की अपेक्षा जनसाधारण से जुड़ने का संकल्प लिया था।" इसके चलते भाजपा ने नगरों, गांवों में जनजागरण अभियान चलाया, रैलियों की भरमार की तथा जनता की ज्वलंत समस्याओं को बुलंद किया। इन कार्यक्रमों पर हुए अमल की रिपोर्टों ने उसके शहरी-ग्रामीण इलाकों में बढ़े जनाधार को दर्शाया। साथ ही सिद्ध किया कि पार्टी के परंपरागत प्रभाव क्षेत्र—उप्र, बिहार, राजस्थान, मप्र, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भी उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई है।

रणनीति: स्थिति मजबूत करने के अलावा भाजपा के पास कोई चारा भी नहीं था। दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता हैं। गत राष्ट्रपति चुनाव में उसे जिस प्रकार अलग-थलग रहने को बाध्य किया गया, राष्ट्रीय मोर्चे से दूर रखा गया और जिस प्रकार सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर कम्युनिस्ट उसे विपक्षी एकता में दरकिनार करने की अपनी मुहिम में निरंतर रहे हैं, उससे यही मार्ग बचा था कि वह अपने को सुदृढ़ कर इतना अपरिहार्य बनाये कि विपक्ष और मूलतः जनता दल उसे अछूत न समझें और उससे तालमेल करने को बाध्य हो जायें।

जहां तक तालमेल का सवाल है, भाजपा और जनता दल, विशेषकर अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, के रिश्तों में निरंतर उतार-चढ़ाव बना रहा है।

ARMA VANI KENDRA

जन से जुड़े : बोट क्लब पर भाजपा सम्मेलन को संबोधित करते हुए आडवाणी

विपक्षी नेता के अपने उदय के साथ भाजपा के कंधों का सहारा लेनेवाले विश्वनाथ प्रताप सिंह को वामपंथियों को अपना 'स्वाभाविक सहयोगी' करार दे एक प्रकार से भाजपा की अवमानना करने में तनिक भी देर न लगी। एक भाजपा नेता के अनुसार इसके दो कारण रहे हैं। एक, फेयरफैक्स विवाद से उन पर अमरीकी एजेंट होने के आरोप की कालिमा धोने के लिए उनका वामपंथ की ओर झुकना स्वाभाविक था। दूसरे, सिंह को विश्वास था कि उप्र उनके नियंत्रण में है। उसमें वह भाजपा की हिस्सेदारी नहीं चाहते थे।

जहां तक वीपी सिंह का सवाल है, एक बार फिर वे भाजपा को गले लगाते-लगाते पुनः मतपरिवर्तन को तत्पर दिखायी देते हैं। इस बार मुद्दा सिद्धांतों—विशेषकर भाजपा-शिवसेना गठबंधन को बनाया है। सिंह के अनुसार, "भाजपा के साथ हमारे बुनियादी मतभेद तो हैं ही। मसलन अल्पसंख्यक आयोग समाप्त करने, संविधान के अनुच्छेद ३७०—जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान है—को खतम करने की भाजपा की मांग से हमारे मेल नहीं खाते। इसके अलावा भाजपा यदि तानाशाह-समर्थक और घृणा के बलबूते अपना जनाधार बढ़ाने-वाली शिवसेना से चुनावी गठबंधन करेगी, तो हमें स्थिति पर पुनर्विचार करने को बाध्य होना पड़ेगा।

विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि शिवसेना से तालमेल न करने का संदेशा सिंह ने एक पत्रकार मित्र द्वारा भाजपा अध्यक्ष को भिजवाया था। किंतु प्रभाव उलटा पड़ा। कारण, भाजपा ने इसे दिशानिर्देश देना समझा। भाजपा नेताओं का कहना है कि हम तो जनता दल से यह नहीं कहते कि वह कम्युनिस्टों अथवा मुस्लिम लीग से समझौता न करे। शिवसेना से हमारा समझौता यदि हुआ भी, तो उसकी सीमा राज्य स्तर तक है। राज्य स्तर पर समझौते की बात स्वयं जनता दल भी कर रहा है। जवाब में जनता दल के वरिष्ठ सांसद मधु दंडवते बोले, "राज्य स्तर पर समझौते के प्रश्न पर कल यदि कोई विपक्षी दल कांग्रेस से समझौते की बात करे, तो क्या उसे भी मानना पड़ेगा? हिंदू कार्ड भुनाने का प्रयास भाजपा चाहे कितना भी क्यों न करे, किंतु उसके उदारवादी नेता भी भलीभांति समझते हैं कि चुनावी समर्थन में इससे एक सीमा तक ही लाभ पहुचंता है। इससे दूरगामी हानि कहीं अधिक।"

ऊहापोह: तालमेल को लेकर ऊहापोह की स्थिति भाजपा की ही नहीं, जनता दल की भी है। उल्लेखनीय है कि भाजपा के साथ रिश्तों में जनता दल की समस्या अंदरूनी है। आपसी कलह व प्रतिस्पर्धा के चलते जो दो खेमे बन गये हैं, उनमें एक भाजपा को साथ ले अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इसके अगुआ देवीलाल हैं जो हरियाणा में भाजपा के साथ मिलकर न सिर्फ साझा सरकार चला रहे हैं, बल्कि उसे जनता दल सरकार भी घोषित कर चुके हैं। दूसरा गुट वह है जो खुलेआम-विरोधी है अथवा कम्युनिस्टों को साथ लेकर चलना चाहता है। इस गुट के प्रमुख नेताओं में विश्वनाथ प्रताप सिंह और अजीत सिंह शामिल बताये जाते हैं। वीपी सिंह की विवशता यदि वामपंथ का दबाव और अपनी गरीब-समर्थक छवि बनाने की है, तो

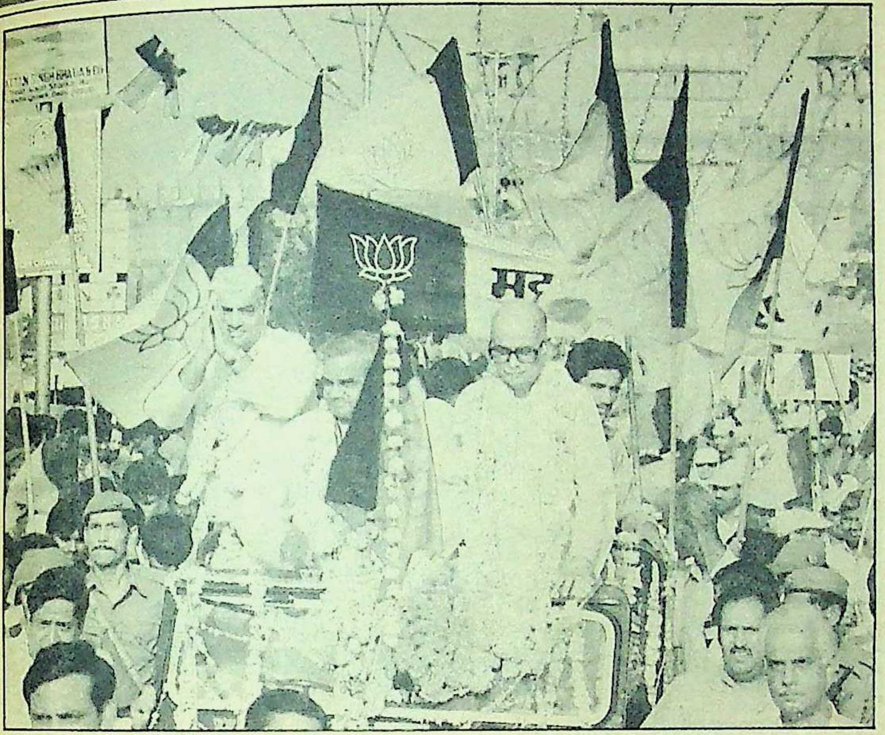

प्रभाव का प्रदर्शन : दिल्ली में भाजपा की रैली

अजीत सिंह के सामने सवाल महत्ता का है। उनका भाजपा से प्रत्यक्ष बैर नहीं। उनका सीधा-सीधा सामना देवीलाल गुट से है, जिसे भाजपा का समर्थन प्राप्त है। अजीत सिंह को कदाचित यही आशंका है कि देवीलाल के मजबूत होने से उनके हितों को धक्का पहुंचेगा, क्योंकि दोनों का जनाधार लगभग एक है।

भाजपा की अपरिहार्यता : जनता दल में चाहे जितना भी असमंजस क्यों न रहा हो, वस्तुस्थिति आज यह है कि लगभग सभी यह समझने लगे हैं कि भाजपा से तालमेल के बिना राजीव गांधी को उखाड़ फेंकना असंभव होगा। इस संबंध में जनता दल सांसद शरद यादव ने 'माया' से कहा, "न हम इतिहास बदल सकते हैं न भूगोल, न तो इस तथ्य को अनदेखा कर सकते हैं कि १९६७ और १९७७ में हमने इनका साथ दिया और लिया। इसीलिए कम्युनिस्टों का विरोध समझ के बाहर है। न ही इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि उनके अपने सुनिश्चित प्रभाव क्षेत्र हैं, खासकर, उत्तर भारत में जहां हार-जीत का फैसला होनेवाला है।" उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत में कम्युनिस्टों का प्रभाव नगण्य है। ऐसी स्थिति में जनता दल का भाजपा से तालमेल लाजिमी हो जायेगा।

भाजपा उत्तर भारत में अपनी निर्णायक भूमिका से कितनी आश्वस्त है, इसका संकेत पार्टी महासचिव माथुर के इस दावे से मिला कि यदि वीपी सिंह उप्र, बिहार में भाजपा का सहयोग लेने का निर्णय नहीं लेते, तो उन्हें स्वयं अपनी सीट जीतने के लिए प० बंगाल जाकर मार्क्सवादियों का पल्लू पकड़ना पड़ेगा।

अधिकांश पर्यवेक्षक भाजपा के आत्मविश्वास और मौजूदा आक्रामक रुख को सीधे-सीधे उसकी दबाव की रणनीति करार दे रहे हैं। लक्ष्य अधिक-से-अधिक सीटों पर अपना दावा पेश कर चुनाव लड़ना है। दिलचस्प तथ्य तो यह है कि शिवसेना से भाजपा नेता महीनों से बातचीत तो अवश्य चला रहे हैं, किंतु उसे किसी निर्णायक दौर पर नहीं ला पाये। भाजपा का मंशा स्पष्ट है, एक ओर वह जनता दल के सिर पर शिवसेना से तालमेल की अपनी नंगी तलवार लटका जनता दल को जल्द-से-जल्द अपने पक्ष में निर्णय के लिए विवश कर सके। दूसरे, तालमेल के समय अपनी मोलतोल की औकात बढ़ा सके। साथ ही जनता दल से तालमेल न होने की स्थिति में अंततः शिवसेना से समझौते का मार्ग खुला रहे।

भाजपा की इसी रणनीति को भांपते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ रुष्ट होते हुए कहा, "जनता दल किसी के भी दबाव में आनेवाला नहीं।" वैसे कुछ राजनीतिज्ञ भाजपा के प्रति वीपी सिंह के वर्तमान रोष का कारण पार्टी की उदयपुर की हाल की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना मानते हैं।

दबाव की रणनीति से इनकार करते हुए भाजपा महासचिव किशनलाल शर्मा ने 'माया' से कहा, "यदि हम इसे दबाव की रणनीति भी मानें, तो भी हम इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकते, जब तक हमें अपनी सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास न हो। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब जनता दल की बारी है। किंतु यह पक्का है कि हम कोई एकपक्षीयं निर्णय माननेवाले नहीं। इसके लिए विचार-विमर्श और समुचित निर्णय पहली शर्त है। हमारे हिसाब से हमारा २०० लोकसभा सीटों पर दावा बनता है। यदि जनता दल ने अलग ही चुनाव लड़ा, तो हम कम-से-कम ३५० सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।"

जहां तक सीटों का सवाल है, भाजपा का दावा परस्पर विरोधी है। वह एक ओर जहां ६० सीटें जीतने की बात कर रही है, वहीं लोकसभा में सबसे बडी ताकत बनने का स्वप्न भी संजोये हुए है। उसका स्वप्न साकार होगा या नहीं, यह कहना तो कठिन है, किंतु आगामी चुनावों में वह महती और निर्णायक भूमिका निभायेगी, इसमें संदेह नहीं। कारण वह सुनियोजित ढंग से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। देश भर में फैले प्रतिबद्ध संघ के नेताओं-कार्यकर्ताओं का उसे समर्थन भी प्राप्त है। समर्पित कार्यकर्ताओं, स्पष्ट कार्यक्रम, लक्ष्य और दिशा की पूंजी होने के बावजूद कमी है, तो 'नकद नारायण' की। जब इसकी चर्चा एक कम्युनिष्ट नेता से चली, तो वे बोले कि जब बनियों की पार्टी का यह हश्र है, तो मजदूरों-किसानों की हमारी पार्टी का क्या हाल होगा ? जवाब दिया भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने। उनका कहना था कि विपक्षी दलों—चाहे वह वामपंथी हों या गैरवामपंथी—की अपनी-अपनी सरकारें हैं। फलतः धन की कमी उन्हें खटकती नहीं। भाजपा को तो छोटे-छोटे चंदों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा से यदि किसी कारण चुनावी तालमेल न हुआ, तो इसका खमियाजा भाजपा से कहीं अधिक जनता दल को भुगतना पड़ेगा। लाभ सीधे-सीधे कांग्रेस के खाते में जायेगा, जिसे पराजित करने का मंसूबा दोनो (भाजपा-जनता दल) पाले हुए हैं। भाजपा की स्थिति ऐसी है कि स्वयं उससे तालमेल को लेकर मार्क्सवादी पार्टी दो खेमे में बंट गयी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु व उनके अन्य साथी जहां भाजपा से तालमेल के पक्षधर हैं, वहीं पार्टी महासचिव ईएमएस नंबूदिरीपाद उससे किसी प्रकार का रिश्ता न बनाने देने के लिए कटिबद्ध नजर आते हैं।

फिलहाल अपना झंडा उठा अकेले चलने को विवश भाजपा अपने शक्ति-प्रदर्शन का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। राजधानी दिल्ली में १० मई की अपनी सबसे बड़ी किसान रैली आयोजित करने की योजना उसकी इसी रणनीति का एक अंग है कि वह मेहनतकशों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करे और शहरों से गांवों तक फैले अपने जनाधार के दावे की पुष्टि करे। चुनावी जंग में सफलता का दारोमदार इन्हीं हथियारों के कुशल प्रयोग पर निर्भर है। इसमें भाजपा कितनी कामयाब होगी, यह तो समय ही बतायेगा।

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ,

इफ्को आंवला परियोजना

भ्रष्टाचार का भांडा कैसे फूटा ?

यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी प्रतिष्ठान का 'गौरव' बतायी गयी थी। किंतु अब वह 'रौरव' नरक की नाईं त्रासद बन गयी है, क्यों और कैसे ?

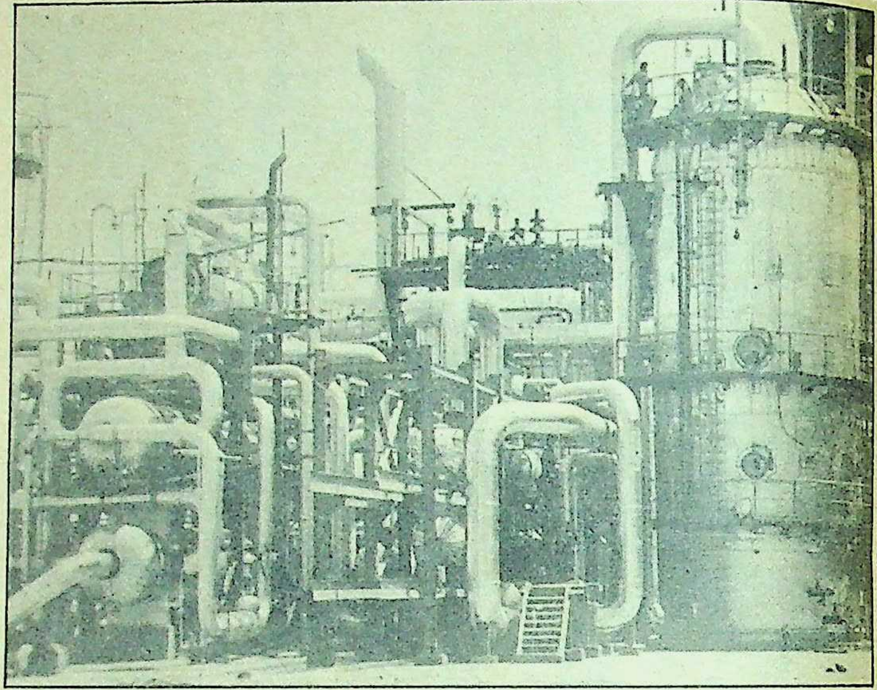

गौरव या रौरव: इफ्को आंवला परियोजना

"हिंदी के पत्रकारों से बात करना उन्हें कतई नापसंद है, क्योंकि वे खास बातों को आम कर देते हैं, देशभर की जनता तक पहुंचा देते हैं। ऐसी हरकतें उन अधिकारियों को, जो दो नंबर के धंधे से आगे बढ़े हैं, कैसे रास आयेंगी ?" यह टिप्पणी है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफ्को) की 'आंवला परियोजना' के एक कर्मचारी की, जो इस बात से क्षुब्ध है कि किसानों के लिए अरबों रु० की लागत से चालू इस परियोजना में हुए करोड़ों के घपले की खबर किसानों तक पहुंचने नहीं दी जाती।

'इफ्को' एशिया में सहकारी क्षेत्र की अग्रणी संस्था है। १९६७ में दो अरब रु० की पूंजी से बहु-इकाई सहकारी संस्था के रूप में स्थापित इफ्को का घोषित उद्देश्य था, उन्नत किस्म के उर्वरक तैयार करना और किसानों को उपलब्ध कराना। शुरू में संस्था इस उद्देश्य की ओर बढ़ती दिखी भी, इसीलिए इसका काफी विस्तार भी हुआ। इसी क्रम में, वर्ष १९८५-८६ में उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के आंवला क्षेत्र में 'आंवला परियोजना' शुरू की गयी। तब इस परियोजना को 'इफ्को' का गौरव कहा गया था। पर साल-डेढ़ साल बाद ही पता चल गया कि इफ्को—खासकर आंवला परियोजना-का मूल उद्देश्य कुछ और ही है। बंबई में नियुक्त इफ्को प्रतिनिधि वीएस धुल ने आंवला परियोजना की कतिपय अनियमितताओं को लेकर जब प्रबंध निदेशक एमएच अवधानी के समक्ष आपत्ति रखी, तब कोई छानबीन जैसी कार्रवाई होने के बजाय उन्हीं का तबादला कर दिया गया। लेकिन भला हो उन आडिटरों का, जिन्होंने 'आंवला परियोजना' में विभिन्न स्तरों पर हुए घालमेल और घोटाले का राजफाश कर ही दिया।

६.९६ अरब रु० की लागतवाली आंवला परियोजना के लिए ३.४६ अरब रु० की विदेशी मुद्रा जुटायी गयी थी। धन की व्यवस्था विश्व बैंक ने की थी। इस परियोजना के सलाहकार सनम प्रोगेति (इटली), हैल्डोर टोप्सा ए/एस (डेनमार्क), प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट (भारत) आदि थे। इफ्को को इस परियोजना से बड़ी उम्मीदें थीं। अप्रैल '८८ में जब इसके तहत उत्पादन शुरू हुआ, तब प्रतिवर्ष ७,२६ लाख टन का उर्वरक-उत्पादन-लक्ष्य रखा गया। शुरू में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। यह देख इफ्को ने इस परियोजना के विस्तार के लिए २.५५ अरब रु० की एक अन्य योजना बना डाली। वर्ष १९९५-९६ में पूरी होनेवाली इस विस्तार-योजना को केंद्र सरकार ने ऋण देने की स्वीकृति भी दे दी थी। लेकिन अब इस विस्तार-योजना की कौन कहे, इसकी जननी आंवला परियोजना तक के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

कार्रवाई पर कार्रवाई : हुआ यह कि आंवला परियोजना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने 'उन्नत किस्म के उर्वरकों' के बजाय भ्रष्टाचार की ऐसी फसल उगायी, जिसे आज लगभग ५० करोड़ रुपयों के घोटाले की संज्ञा दी जा रही है। गत ६ जनवरी को संस्था की आडिट रिपोर्ट से घोटालों का रहस्योद्घाटन हुआ। केवल एक खाते के आडिट में वित्तीय अनियमितता के लगभग २० मामले सामने आये, जिनमें इफ्को को करोड़ों रु० की चपत लगा दी गयी थी (देखें बाक्स)। आडिट रिपोर्ट आते ही इफ्को मुख्यालय में खलबली मच गयी। रिपोर्ट को पूर्णतया गोपनीय रखा गया था, क्योंकि घोटालों में चोटी के कई अधिकारियों के हाथ होने की बात उसमें कही गयी थी। फिर इसी ७ फरवरी को इफ्को के अध्यक्ष घनश्याम सिंह समेत पांच सदस्यीय बैठक में उपर्युक्त घोटालों के लिए आंवला परियोजना के कार्यकारी निदेशक एसआर सहोर को निलंबित करने का निर्णय किया गया। प्रबंध निदेशक एमएच अवधानी हैदराबाद के पास बनी अपनी नयी कोठी में गृहप्रवेश के लिए छुट्टी पर गये थे। इसलिए सहोर का निलंबन आदेश कार्यकारी निदेशक (पी एंड आर) आरके गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी हुआ। गुप्ता बताते हैं, "हालांकि मैं पद के लिहाज से सहोर साहब से काफी जूनियर हूं, लेकिन इफ्को के नियम की धारा ४३ (१९) के तहत कोई जूनियर अफसर भी अपने सीनियर अफसर को 'सस्पेंड' कर सकता है।"

अपने निलंबन की खबर सुनकर एसआर सहोर जरा भी विचलित नहीं हुए। सहोर की राजनीतिक पहुंच इतनी ऊंची है कि वे किसी की परवाह नहीं करते। निलंबन-आदेश प्राप्त होते ही उन्होंने अपने संरक्षक और उर्वरक विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री आर प्रभु से संपर्क साधा। इसका असर हुआ और केंद्रीय उर्वरक विभाग के संयुक्त सचिव केपी श्रीवास्तव ने ९ फरवरी'८९ को अपने आदेशपत्र (संख्या १३९/८९) के जरिये सहोर का निलंबन रद्द कर दिया। इफ्को अध्यक्ष को भेजे गये इस पत्र में सहकारी समिति नियम १९८५ की धारा ४७ का हवाला देते हुए कहा गया है, "सरकार किसी सहकारी संस्था के मामले में दखल दे सकती

है। चूंकि सहोर के निलंबन का निर्णय प्रबंध निदेशक एमएच अवधानी की अनुपस्थिति में किया गया, इसलिए मंडल के समक्ष प्रबंधकों का दृष्टिकोण पेश नहीं किया जा सका, अतः यह निलंबन गैर-कानूनी है।''

दरअसल, उपर्युक्त नियमों का हवाला देकर सहोर का निलंबन रद्द करनेवाले उर्वरक विभाग के संयुक्त सचिव श्रीवास्तव ने अपने पत्र में अधूरी जानकारी दी है। उन्हें मालूम नहीं था कि जिस नियम-कानून का हवाला देकर उन्होंने सहोर का निलंबन रद्द किया, उस नियम के तहत सरकार केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जो सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हों। सहोर का निलंबन किस दृष्टि से सार्वजनिक हितों के विरुद्ध था, आदेशपत्र में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।

ऊपर का संरक्षण: बहरहाल, निलंबन रद्द होते ही सहोर ने पुनः कार्यभार संभाल लिया। उनके कार्यभार संभालते ही प्रबंध निदेशक अवधानी भी अवकाश से लौट आये। इस पर इफ्को के एक सूत्र का कहना है, ''हकीकत यह है कि प्रबंध निदेशक अवधानी का सहोर को खुला संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि जब कभी सहोर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई आवाज उठी, तब या तो अवधानी अचानक किसी बहुत जरूरी काम से कहीं चले जाते या बीमार पड़ जाते थे। इस तरह सहोर का समर्थन करने के साथ ही वे अपने बचाव के प्रति भी सदैव जागरूक रहे।''

वर्ष १९८८ में आंवला परियोजना में हुए घोटालों को लेकर इफ्को संचालक मंडल की लगभग आधा दर्जन बैठकें हुईं। लेकिन प्रबंध निदेशक अवधानी इन बैठकों में होनेवाली चर्चा से बचने के लिए हर बार छुट्टी पर चले जाते। १६ अगस्त '८८ को हुई संचालक मंडल की बैठक में अवधानी को लिखित निर्देश दिया गया था कि वे पूरी आंवला परियोजना का आडिट करायें। लेकिन उन्होंने केवल एक खाते 'ट्रांसपोर्टेशन' का ही आडिट कराया। ३ अक्तूबर '८८ को संचालक मंडल द्वारा उन्हें पुनः निर्देश दिया गया कि वे पूरा आडिट करायें। लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

६ जनवरी '८९ को ट्रांसपोर्टेशन खाते की आडिट रिपोर्ट आ गयी, जिसे २३ जनवरी को संचालक मंडल की बैठक में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन खाते में लगभग तीन करोड़ रु० का घोटाला बताया गया था। घोटाले में ६५ लाख रु० का मामला तो गबन जैसा था। संचालक मंडल की ओर से प्रबंध निदेशक अवधानी को निर्देश दिया गया कि वे संबद्ध अधिकारी से उक्त रकम की वसूली करें। लेकिन वसूली आदेश जारी करने के

एमएच अवधानी

एसआर सहोर

आर प्रभु

कैसे-कैसे घोटाले ?

इफ्को आंवला परियोजना में हुए घपले-घोटालों की जो सूची और विवरण आडिट रिपोर्ट में दर्ज है, वह इतना विस्तृत है कि किसी पत्र-पत्रिका में उसे पूरी तरह देना संभव नहीं है। जहां सिर्फ ट्रांसपोर्ट (परिवहन) के मद में इतने घपले हों, वहां शेष सभी खातों में कितने हुए होंगे, इसका अनुमान ही किया जा सकता है, अथवा व्यापक जांच से ही जायजा लिया जा सकता है। फिर भी, कुछ मोटे उदाहरण लिये जा सकते हैं जो बताते हैं कि आंवला परियोजना में कैसी लूट मची रही है मसलन:

ठेके की राशि: परियोजना के निर्माण के दौरान भिवंडी (महाराष्ट्र) से आंवला तक सामान पहुंचने के लिए दो ठेकेदारों, अग्रवाल कैरियर्स तथा इकानामिक ट्रांसपोर्टर्स को २१ लाख रुपए का ठेका दिया गया। लेकिन मार्च '८६ से मार्च '८७ तक यह राशि २१ लाख रुपए से बढ़कर १.०६ करोड़ रुपए तक जा पहुंची। वर्ष ८७ में उपर्युक्त ठेकेदारों द्वारा बगैर पूरे दस्तावेज प्रस्तुत किये ही उन्हें ६५ लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया।

काम ट्रक का नाम ट्रेलर का: आडिट रिपोर्ट (पृष्ठ १११) के अनुसार बंबई पोर्ट से कुछ सामान ट्रकों में लादकर आंवला भेजा गया, पर भुगतान ट्रक के बाजाय ट्रेलर का किया गया। इस मामले में इफ्को को साढ़े ग्यारह लाख रुपए की चपत लगी।

दुगनी दूरी का भुगतान: आडिट रिपोर्ट (पृष्ठ १११) पर कहा गया है कि जमशेदपुर से कुछ सामान आंवला पहुंचाने का ठेका दिया गया था। राष्ट्रीय मार्ग से जमशेदपुर (वाया रांची-वाराणसी-लखनऊ) ११२६ किलोमीटर है, लेकिन ठेकेदार को १९९६ किलोमीटर के हिसाब से १० लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार सतना से आंवला की दूरी ८९२ किलोमीटर है, पर १५०३ किलोमीटर की दूरी दिखा कर ९ लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। राउरकेला से आंवला १२२२ किलोमीटर पड़ता है, लेकिन १९८६ किलोमीटर बताकर ८.६१ लाख रुपए अधिक भुगतान हुआ।

एक बिल दो भुगतान: आडिट के दौरान एक ऐसा मामला भी पकड़ा गया जिसमें एक ही बिल का दो बार भुगतान किया गया। इस मामले में इफ्को को चपत लगी। इसी प्रकार कुछ मामलों में सामान की तत्काल जरूरत बता कर ठेकेदारों को ५.९५ लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया, जबकि ठेकेदारों ने सामान काफी विलंब से सप्लाई किया।

गलत परिणाम: एक अन्य घोटाले में केबिल ड्रमों की ढुलाई के मद में २५.६७ लाख रुपए का गलत तथा अतिरिक्त भुगतान किया गया। केबिल भेजा तो किसी वाहन से गया, लेकिन भुगतान दूसरे वाहन के नाम पर कर दिया गया। इसी तरह परिमाण (नाप) का गलत आकलन करके इफ्को को ६० लाख रुपए का चूना लगाया गया। ऐसे मामलों में जिस सामान की ढुलाई हुई, उसकी ऊंचाई २.५ मीटर से कम थी, लिहाजा ढुलाई के लिए 'लो बेड ट्रेलर' की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी जरूरत बता कर १२.४१ लाख रुपए का ज्यादा भुगतान कर दिया गया। आडिट रिपोर्ट में ऐसे कुल मामलों में ६० लाख रुपए के भुगतान का जिक्र है, जिनमें परिमाण की जांच नहीं हो सकी।

सूत्रों का कहना है कि आंवला परियोजना की स्थापना के दौरान भी ऊंचे स्तर पर कमीशन बाजी हुई थी। परियोजना की स्थापना के दौरान मेसर्स केलांग इंडिया लिमिटेड (न्यूजर्सी) नामक संस्था ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय में एक प्रार्थनापत्र देकर कहा था, ''वर्तमान मूल्यों के आधार पर आंवला परियोजना जैसी समान तकनीक और डिजाइन के प्लांट को केवल ५८० करोड़ रुपए में बनाया जा सकता। आंवला परियोजना के समान नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, केवल ५८४ करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जबकि आंवला परियोजना की लागत ६९६, करोड़ रुपए दिखायी गयी है।''

—लखनऊ ब्यूरो

बजाय अवधानी लंबी छुट्टी पर निकल गये। तब इस मामले की जांच के लिए एक उपसमिति बनायी गयी, जिसमें इफ्को अध्यक्ष घनश्याम सिंह, संयुक्त सचिव (केंद्रीय कृषि मंत्रालय) आरके आनंद के साथ लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के पुत्र सुरेंद्र जाखड़ भी शामिल थे। इस समिति ने ७ फरवरी '८६ को एक बैठक निश्चित की थी, जिसकी पूर्वसूचना प्रबंध निदेशक अवधानी को भी दे दी गयी थी। लेकिन अवधानी पुन: अवकाश पर चले गये। इस तरह उनकी गैरमौजूदगी में ही सहोर को निलंबित कर दिया गया था।

राजनीतिक पहुंच: अप्रैल '८८ में आंवला परियोजना के कुछ कर्मचारियों की ओर से इफ्को मुख्यालय को एक आरोपपत्र भेजा गया था। उसमें अधिकांश आरोप अवधानी तथा सहोर के ऊपर लगाये गये थे। संभवत: उसी के आधार पर इफ्को अध्यक्ष ने आंवला परियोजना का अंतरिम आडिट कराने का निश्चय किया था। दूसरी ओर अपना नाम न छापने का अनुरोध करनेवाले इफ्को मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, "चाहे जितनी बार भी आडिट हो जाये, उन सबकी रिपोर्ट घोटालों के समुद्र में डूब जायेगी, क्योंकि यहां के भ्रष्ट अफसरों के काले खजानों का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के गलियारे में गड़े स्तम्भों तक पहुंचता है।"

आंवला परियोजना का चेहरा पहले काफी साफ सुथरा था। लेकिन अब इस चेहरे पर राजनीतिकों के पंजे तमाम खरोंचे उभार चुके हैं। दो केंद्रीय मंत्रियों की आपसी लड़ाई का अखाड़ा बनी यह महत्वपूर्ण परियोजना अधमरी-सी हो चुकी है। कहा जाता है कि इफ्को के पूर्व अध्यक्ष जी श्रीनिवास रेड्डी के कार्यकाल में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। उनके तथा प्रबंध निदेशक अवधानी के बीच गहरा तालमेल था, पर घनश्याम सिंह के अध्यक्ष बनते ही तमाम बखेड़े उठ खड़े हुए। घनश्याम सिंह की शुरू से ही अवधानी से नहीं पटी। इन्हीं आपसी मतभेदों के कारण आंवला परियोजना में गुटबंदी की बुनियाद पड़ी। सहोर को अपने साथ लेकर अवधानी एक गुट के मुखिया बन गये, तो बाकी अफसरों की कमान घनश्याम सिंह ने सम्भाल ली। दोनों गुटों की राजनीतिक पहुंच भी कम नहीं है। अध्यक्ष घनश्याम सिंह के केंद्रीय कृषिमंत्री भजनलाल से गहरे संबंध हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पुत्र सुरेंद्र जाखड़ भी उनके साथ हैं। दूसरी ओर प्रबंध निदेशक अवधानी तथा सहोर को केंद्रीय राज्यमंत्री आर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है, जो स्वतंत्र रूप से उर्वरक विभाग देखते हैं। इफ्को भी इसी विभाग के तहत आता है। यही कारण है कि पिछले छह वर्षों से प्रबंध निदेशक अवधानी अपने कार्यकाल में लगातार वृद्धि कराने में सफल रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि केंद्रीय कृषिमंत्री भजनलाल तथा इसी विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री आर प्रभु के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा पुरानी है।

फाइल दिल्ली में: अलबत्ता, अब तक जो घोटाले उजागर हुए हैं, वे केवल एक ही खाते (ट्रांस्पोर्टेशन) के हैं, क्योंकि पूरा आडिट नहीं कराया गया। ३४, नेहरू प्लेस दिल्ली स्थित इफ्को मुख्यालय के विश्वस्त सूत्रों का कहना है, "यदि आंवला परियोजना के प्रत्येक खाते की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करायी जाये, तो कम से कम ६० करोड़ रुपयों के घोटाले और सामने आयेंगे।" फिलहाल कार्रवाई के नाम पर मामले की सारी फाइलें प्रधानमंत्री सचिवालय में मंगा ली गयी हैं। आंवला परियोजना के घोटालों का मुद्दा भीतर ही भीतर इतना तूल पकड़ चुका है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन के साथ ही इफ्को के कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिये जाने की संभावना बन चली है। सहोर के निलंबन और बहाली के बाद से इफ्को के उन वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने बचाव की कोशिशें अभी से शुरू कर दी हैं, जिनके गले पर खतरे की तलवार लटक रही है।

१७ फरवरी को जब 'माया' ने 'आंवला परियोजना' का दौरा किया, तब महाप्रबंधक एसपी गुप्ता को छोड़कर, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। परियोजना गेट के बाहर से जब फोन पर महाप्रबंधक गुप्ता से संपर्क किया गया, तो उनका कहना था, "यहां आकर आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। हम हिंदी प्रेस को 'लाइक' नहीं करते। ऊपर से आदेश है कि हम हिंदी जर्नलिस्टों से बात न करें।"

—राजीव सक्सेना, बरेली से

चुटकी की चुटकियां
ज़िन्दगी की भोली-भाली मस्तियां
चुटकी पान मसाला प्यार के रिश्तों में एक अनोखी ताज़गी और मीठी-मीठी महक लाता है। हर मौके, हर महफ़िल में रंग जमाता है। सौंफ़, छुआरा और इलायची वाला चुटकी पान मसाला कितना है निराला!
अब नये सजधज के साथ नये आकर्षक पॉउच पैक में!
Chutki
Chutki
प्यार का मस्ती भरा एहसास
चुटकी पान मसाला!

एक गिनी चुनी वस्तु जिस पर आयु अपना चिन्ह नहीं छोड़ती

केल्विनेटर रेफ्रिजरेटर सुशोभित रूप से क्रियाशील रह कर, वर्षों वर्ष उसी कुशलता से कार्य करता है।

इसकी लम्बी आयु का एक कारण है इसका 'पावर-सेवर' 'कॉम्प्रेसर'। यह शीघ्र ठंडा करता है तथा इस से शीघ्र बर्फ़ बनाता है। चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो। वोल्टेज का कितना भी उतार चढ़ाव इसके कुशल कार्य में विघ्न नहीं डाल सकता। तथा यह न्यूनतम बिजली की खपत करता है।

केल्विनेटर का एक और आश्चर्यजनक गुण है — इसमें वस्तुएं रखने की विशाल क्षमता। इसके कोने-किनारे रहित विशिष्ट अन्दरूनी डिज़ाइन में अधिकतम स्थान का उपयोग हो सकता है।

सुदृढ़, सम्पूर्ण-स्टील निर्माण तथा मज़बूत ए बी एस लाइनर इसके अन्दरूनी एवं बाहरी भाग को अधिक मज़बूती तथा अधिक टिकाऊपन प्रदान करते हैं।

आपके चयन के लिए यह विभिन्न मॉडलों तथा आकर्षक रंगों में उपलब्ध है।

जब आप जीवन भर में एक बार ही रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहें तो केल्विनेटर ही खरीदें।

विक्रय एवं सर्विस के लिए

एक्सपो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टॉवर, 26, राजिन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली-110 008.

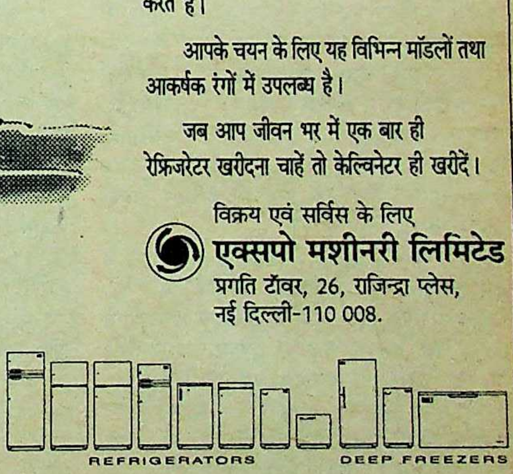

केल्विनेटर

रेफ्रिजरेटर

"इसकी ठण्डक...बेमिसाल!"

Mutual-4711 Ed HN

स्वामी पर दो करोड़ का दावा

हेगड़े बंबई की अदालत में क्यों गये ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के गंभीर आरोपों से आजिज होकर जनता दल उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े को डा० स्वामी पर २ करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोंकना पड़ा है। किंतु उनके अदालत के चयन ने विरोधियों को छींटाकशी के नये अवसर दिये हैं। क्या वजह है कि हेगड़े ने दावा कर्नाटक में न करके बंबई उच्च न्यायालय में किया ?

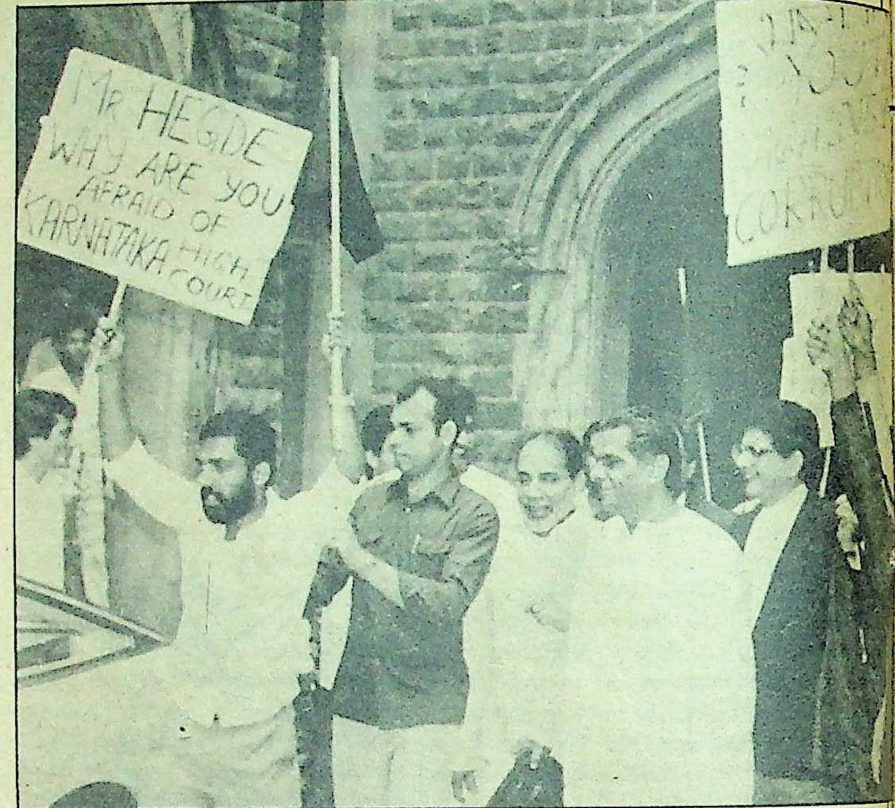

अदालत तक विरोध : बंबई हाईकोर्ट के समक्ष विरोधियों का प्रदर्शन

रामकृष्ण हेगड़े और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के बीच जारी तानाकशी ने ७ मार्च को नया मोड़ तब ले लिया जब हेगड़े ने मानहानि कानून के तहत स्वामी पर दो करोड़ रुपए हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया। बंबई उच्च-न्यायालय में मुकदमा दायर करके हेगड़े ने स्वामी के मुंह पर रोक लगा दी, क्योंकि जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, छींटाकशी की गुंजाइश नहीं। साथ ही हेगड़े ने यह भी साबित कर दिया कि उन्हें भी जवाबी हमला करना आता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों में स्वामी ने हेगड़े पर कई तरह के आरोप लगाये थे। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने कर्नाटक सरकार के टेप-कांड का मसला उजागर किया था, जिसके चलते राम कृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर १० जनवरी '८९ को स्वामी ने दिल्ली के संवाददाता सम्मेलन में हेगड़े व उनके परिवार पर भूखंड बिक्री में घोटाले से ३ अरब रुपए कमाने का आरोप लगाया। स्वामी का दावा था कि बंगलौर में तो मौके की १० हजार एकड़ जमीन हेगड़े ने अपने खास लोगों की गृह निर्माण समितियों को दी ही, अन्य शहरों में भी उन्होंने यही किया।

आरोपों की वर्षा : स्वामी ने यह भी बताया कि प्रवासी भारतीयों की गृह निर्माण संस्था को औने-पौने दाम पर जमीन देकर हेगड़े परिवार ने एक अरब रुपए की कमाई की थी। स्वामी ने इस मामले में हेगड़े के दामाद मनु निचानी का हाथ भी बताया था।

स्वामी द्वारा हेगड़े पर लगाये जा रहे आरोपों का सिलसिला यहीं पर खतम नहीं हुआ था। २७ जनवरी को स्वामी ने एक बार फिर संवाददाताओं को जमा किया था। उनके निमंत्रण पर समाचार-पत्रों के संवाददाता तो पहुंचे ही, दिल्ली दूरदर्शन की टीम भी पूरे इंतजाम के साथ उनके द्वारा किये जाने वाले रहस्योद्घाटन को सुनने पहुच गयी। इस संवाददाता सम्मेलन में डा० स्वामी ने हेगड़े पर यह आरोप लगाया था कि हेगड़े ने विदेशी बैंक में १५० करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। इसी दौरान उन्होंने यह भी बताया था कि जब विश्वनाथ प्रताप सिह वित्तमंत्री थे, तो उन्होंने राजस्व सचिव विनोद पांडे को हेगड़े के विदेशी बैंक खातों का पता लगाने का आदेश भी दिया था। मजे की बात तो यह है कि स्वामी हेगड़े पर आरोपों की बौछार करते समय यह भी कह गये थे, "हेगड़े राजीव से बड़े झूठे हैं।"

जाहिर है, स्वामी के आरोप भले झूठे ही क्यों न हों, हेगड़े की साफ-सुथरी छवि को धूमिल करने के लिए काफी थे। अल्प अवधि में कई बार स्वामी द्वारा किये गये प्रहारों ने हेगड़े को चिंतित कर दिया था। हालांकि इस बीच वे स्वामी द्वारा लगाये गये आरोपों की सफाई देने में मसरूफ थे, किंतु सफाई से स्वामी का मुंह तो बंद हो नहीं रहा था। लिहाजा हेगड़े ने आगे-पीछे सोचे बिना वकील महेश जेठमलानी की मार्फत स्वामी को कानूनी नोटिस भेज दिया, जिसमें उन्होंने स्वामी से आरोपों का खंडन करने का आग्रह किया, साथ ही धमकी भी दी थी कि यदि स्वामी ने निश्चित अवधि में अपने आरोपों का खंडन नहीं किया, तो उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया जायेगा। कानूनी नोटिस मिलने पर भी स्वामी पीछे नहीं हटे। बल्कि उन्होंने अपने आरोपों को दोहराया तथा आरोपों के सच होने का दावा किया। साथ ही, यह भी कहा कि उन्हें नोटिस और मुकदमे की परवाह नहीं। उन्होंने नोटिस को कचरा पेटी में डाल दिया है।

विकल्प का अभाव : ऐसी स्थिति में हेगड़े के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि वे स्वामी का मुंह बंद करने के लिए उन पर मुकदमा दायर करते, क्योंकि उनका यह सोचना गलत साबित हो गया था कि कानूनी नोटिस की धौंस में आकर स्वामी अपने आरोप वापस ले लेंगे। नतीजतन पांच मार्च को हेगड़े बंबई के जनता पार्टी के महासचिव तथा जाने-माने वकील प्रद्युम्न वधेका के साथ सवेरे के विमान से बंबई पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले राम जेठमलानी और उनके बेटे महेश जेठमलानी से लंबी बातचीत की। दीवानी मुकदमों में तेजी से उभर रहे महेश के सहयोगी सतीश माने शिंदे भी बातचीत के दौरान मौजूद थे।

हेगड़े का इरादा था कि जल्दी मुकदमा दायर किया जाये, ताकि स्वामी की जुबान पर लगाम लगे। क्योंकि उन्हें इस बात का अहसास हो गया था कि सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा पूर्व मंत्री देवगौड़ा

मामूली हथकंडों से मानने वाले नहीं। हाल में ही स्वामी ने मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई की अध्यक्षता में हुई कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में कथित गुप्त दस्तावेज का नंबर भी बता दिया था (७ जुलाई '८८ को केबिनेट नोट आरयूडी-१८० सीईआई ८८ विषय-३३३/८८)।

मुकदमा दायर करने के संबंध में हेगड़े का सुझाव था कि सिर्फ एक रुपए का सांकेतिक हर्जाना मांगा जाये। हालांकि उन्हें इस बात का डर था कि वे जो हर्जाना भी मांगेंगे, स्वामी की फब्ती यही होगी, 'उनकी इतनी ही कीमत है? इससे ज्यादा तो उन्होंने भ्रष्टाचार में कमाया?'

हेगड़े की एक रुपए की सांकेतिक हर्जाने की राय पर कोई वकील सहमत नहीं हुआ। इस संबंध में एक वकील ने हेगड़े से कहा, "वह एक रुपए भेजकर फुर्सत पा लेगा और आपके खिलाफ आरोपों की नयी झड़ी लगा देगा? फिर आप क्या कर लेंगे?" अंत में यह तय हुआ कि मुख्यमंत्री रह चुके एक राष्ट्रीय दल के उपाध्यक्ष की सार्वजनिक बदनामी करने के लिए एक करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की जाये तथा अदालत से एक करोड़ रुपए अतिरिक्त हर्जाने की मांग की जाये। आपसी सलाह मशविरा और वकीलों की राय के बाद यह तय हुआ कि मुकदमे का खर्च आदि जोड़कर दो करोड़ रुपए हर्जाने का दावा करना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि यह रकम इतनी बड़ी होगी कि स्वामी को मुंह बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नतीजतन बंबई हाईकोर्ट में स्वामी के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया।

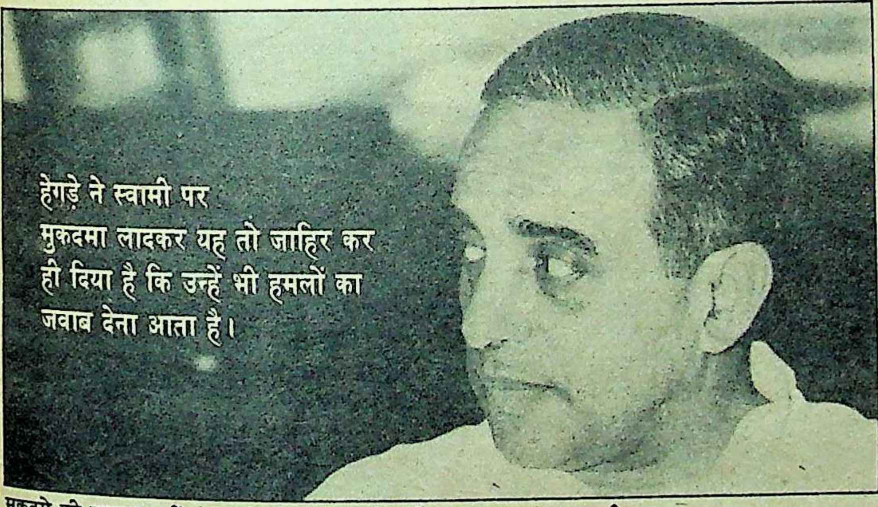

हेगड़े ने स्वामी पर मुकदमा लादकर यह तो जाहिर कर ही दिया है कि उन्हें भी हमलों का जवाब देना आता है।

मुकदमे की परवाह नहीं : अंधाधुंध आरोप लगाने वाले डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी

मजे की बात यह है कि मुकदमा दायर होते ही मुकदमे को लेकर तरह-तरह की बातें प्रकाश में आने लगीं। कुछ लोगों का सवाल है कि जब राम जेठमलानी और महेश जेठमलानी ने मुकदमे के सारे अदालती कागजात तैयार किये थे, तो वकालतनामे पर सतीश माने शिंदे तथा रेशमा रूपारेल के नाम क्यों लिखे गये? हेगड़े के एक निकट सूत्र ने इस संबंध में 'माया' को बताया, "निस्संदेह राम जेठमलानी का जिरह करने में कोई सानी नहीं, किंतु उनके जनता दल सांसद होने की वजह से दावा महज राजनीतिक कलह का मुकदमा बन कर रह जाता।" सूत्र ने यह भी बताया कि सच तो यह है कि राम जेठमलानी खुद चाहते थे कि मानहानि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा चरित्र हनन जैसे मामलों पर वे खुद प्रकाश डाले, किंतु पार्टी की छवि को ध्यान में रखकर उन्हें परदे के पीछे का सहयोगी बनना पड़ा।

मुकदमे पर संदेह : इसके अलावा राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी सबकी जुबान पर है कि बंगलौर के बजाय बंबई उच्च न्यायालय में दावा क्यों ठोंका गया? इस संबंध में हेगड़े का कहना है कि चूंकि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए हो सकता था कि अपनी स्थिति कमजोर देखकर डा० स्वामी न्यायपालिका की ईमानदारी पर उंगली उठाते। इसलिए उन्होंने यह बेहतर समझा कि कर्नाटक में मुकदमा न दायर करके किसी और शहर से यह लड़ाई लड़ी जाये।

हालांकि जनता दल नेता प्रद्युम्न वधेका ने 'माया' को दूसरा कारण बताया। उनके अनुसार, "बंबई तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ही ऐसे हैं, जहां 'ओरिजिनल साइड' है। यानी सेशन कोर्ट में जाये बिना सीधा दावा किया जा सकता है। फिर बंबई उच्च न्यायालय में किसी भी रकम के दीवानी मुकदमे के लिए अधिकतम अदालती शुल्क १५ हजार रुपए हैं, जबकि आमतौर पर दीवानी दावे की १० प्रतिशत रकम फीस के रूप में जमा होती है।" जाहिर है, दो करोड़ के दावे पर हेगड़े को २० लाख रुपए जमा करने पड़ते।

मजे की बात तो यह है कि स्वामी समर्थक जनता पार्टी धड़े के बंबई के अध्यक्ष जगदीश शेट्टी ने मुकदमे के दिन बंबई हाईकोर्ट के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया। ५०-६० व्यक्ति हाथों में तख्तियां लिये थे, जिन पर लिखा था 'अदालती फीस बचाने के लिए जिस राज्य के नेता ने कोर्ट बदला, उस कर्नाटक की प्रजा का क्या होगा?'

जिस समय हेगड़े जनता दल समर्थकों के साथ हाईकोर्ट की इमारत से बाहर आ रहे थे, उस समय 'हेगड़े वापस जाओ,' 'विदेशों से धन वापस लाओ' जैसे नारे लगाये गये। हेगड़े इस तरह के नारों को सुनकर आगबबूला हो उठे और वकील तथा समर्थकों के रोकने पर भी नारेबाजों को जवाब देने के लिए मुड़े और कहा, "अगर तुम लोगों को मेरे विदेशों में जमा धन की मालूमात है, तो खाता नंबर बताओ और मुझसे 'ब्लैंक चेक' ले जाओ। क्रोध से हेगड़े का चेहरा तमतमा रहा था। वे इस हरकत से बहुत नाराज थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मुकदमा दायर होने के बाद भी इस तरह का प्रदर्शन किया जायेगा।

छवि की चिंता : इस संबंध में जब 'माया' ने हेगड़े से संपर्क किया, तो वे बोले, "मैं नहीं जानता कि स्वामी कांग्रेस के एजेंट हैं या नहीं, परंतु यह तो सच है कि वे सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार पर मौन हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, परंतु मेरी ईमानदार, साफ-सुथरी राजनीतिक छवि तथा जनता दल में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति से वे खार खाये बैठे हैं।"

जहां तक हेगड़े द्वारा बंबई में मुकदमा दायर करने की बात है, इसका एक और कारण भी है। डा० स्वामी ने आरोप लगाया था कि प्रवासी भारतीयों की गृह निर्माण संस्था के बिल्डर बंबई के 'लोखंडवाला प्रिमाइसेस लिमिटेड' हैं। आरोप में यह भी कहा गया था कि इस बिल्डर के हेगड़े के दामाद मनु से आर्थिक रिश्ते हैं। कहा जाता है कि हेगड़े ने बंबई में इसलिए और भी मुकदमा दायर किया, ताकि डा० स्वामी ने जो आरोप लगाये हैं, उनका उन लोगों के गृहस्थान में फैसला हो जिनको आरोप में आधार बनाया गया है।

कुछ भी हो, हेगड़े ने स्वामी की जुबान पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जो मुकदमा दायर किया है, उससे स्वामी का मुंह बंद हो या न हो यह अलग बात है, किंतु इतना तो है कि इससे राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ेगी। हालांकि हेगड़े को आशा है कि आम चुनाव के पहले फैसला आने से ऐन चुनाव के मौके पर उन्हें फायदा होगा, लेकिन वकीलों को ३०० दिन में निर्णय आने की संभावना नजर नहीं आती। स्थिति यह है कि हेगड़े के मुकदमा दायर करने के दूसरे दिन ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने हेगड़े सरकार की खिंचाई करते हुए कहा, "कर्नाटक में उनके (हेगड़े) जमाने में ३२ हजार शराब की दूकानों के ठेके दिये गये, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ साढ़े चार हजार शराब की दूकानें हैं। इसलिए उनका शराब बंदी का नारा भी थोथा है।" मुकदमे का फैसला कब और क्या होगा, यह तो फिलहाल नहीं बताया जा सकता, इतना जरूर है कि हेगड़े ने स्वामी पर मुकदमा लादकर यह तो जाहिर कर ही दिया है कि उन्हें भी हमलों का जवाब देना आता है।

—बंबई ब्यूरो

राजीव गांधी के चुनाव-क्षेत्र में विज्ञान प्रदर्शनी

३० करोड़ रुपए की होली का राज क्या है ?

प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सहमति और शिरकत का भरपूर उपयोग करते हुए, उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में, ३० करोड़ रुपए के भारीभरकम खर्च पर, हाल ही जो भड़काऊ 'विज्ञान प्रदर्शनी' आयोजित की गयी, उसका घोषित प्रचारित उद्देश्य था, विज्ञान और टेक्नोलाजी को गांव तक ले जाना। लेकिन हुआ क्या? रकम चीरने, गांववालों की जमीन हड़पने, राजनीति चमकाने और तरह-तरह के फायदे उठाने का यह महानाटक आखिर किन लोगों ने, किस तरह रचा और खेला?

चौंकूं या चौंकाऊं? : विज्ञान प्रदर्शनी के 'समर्पण समारोह' में राजीव गांधी

अमेठी संसदीय क्षेत्र के गौरीगंज इलाके में लगायी गयी 'विज्ञान एवं तकनीकी प्रदर्शनी', ग्रामीण जनता के लिए मनोरंजनपूर्ण तमाशा थी। इस आंडबरपूर्ण आयोजन में खर्च हुए तकरीबन ३० करोड़ रुपए में राजनीतिज्ञों और अफसरों की कथित बंदरबांट दीर्घकालिक चर्चा का विषय बन गयी है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस प्रदर्शनी के आयोजन का प्रत्यक्ष उद्देश्य यह बताया गया था कि प्रदर्शनी देखकर गांव और विशेषकर अमेठी, की जनता को विज्ञान और तकनीक की अच्छी जानकारी मिलेगी। शायद इसीलिए लखनऊ से लेकर प्रदर्शनी स्थल तक के १२० किलोमीटर लंबे मार्ग पर जगह-जगह लगाये गये बैनरों में लिखा गया था, "मैं चाहता हूं कि विज्ञान और टेक्नोलाजी भारत के ग्रामीण जीवन का अंग बने—राजीव गांधी।"

इस घोषित उद्देश्य के अलावा प्रदर्शनी के आयोजकों का एक अघोषित उद्देश्य भी था। वह क्या था, सिवा इसके कि प्रदर्शनी की आड़ में वे अपना हित साधन कर लें? ४ मार्च से लेकर १५ मार्च तक आयोजित यह प्रदर्शनी यद्यपि १२ मार्च से ही उजड़नी शुरू हो गयी थी, लेकिन १५ मार्च के बाद गांववालों की २६ एकड़ जमीन पर, जहां प्रदर्शनी लगी थी, अब प्रियदर्शिनी महिला विद्यापीठ नामक तथाकथित संस्था ने कब्जा कर लिया है। गांववाले प्रदर्शनी और संस्था दोनों को 'षड्यंत्र' कह रहे हैं। इस संस्था के सर्वेसर्वा गौरीगंज के चर्चित व्यक्ति जगदीश पीयूष है।

महत्वाकांक्षाओं का मिलन: पिछले वर्ष नवंबर में मुंगेर (बिहार) के सांसद डीपी यादव की महत्वाकांक्षा ने जोर मारा कि वे किसी भी तरह दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर लें। डीपी यादव, राष्ट्रीय बंजर भूमि और ग्रामीण विकास संस्थान, नयी दिल्ली के चेयरमैन हैं। उनके दिमाग में यह बात आयी कि अपने संस्थान के माध्यम से अगर वे अमेठी संसदीय क्षेत्र में कोई कार्यक्रम चलायें तो इससे राजीव गांधी खुश हो जायेंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने अमेठी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी कैप्टन सतीश शर्मा से बात की। सतीश शर्मा ने सुझाव दिया कि क्षेत्र में जहां बंजर जमीन पड़ी है, उसे उपजाऊ बनाने का कार्य यह संस्थान प्रदेश सरकार की मदद से करे। जाहिर था, अगर डीपी यादव यह कार्य शुरू कराते, तो उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री और सतीश शर्मा को ही जाता, क्योंकि अमेठी की जनता अपने इलाके में हुए सभी विकास-कार्यों का श्रेय मुख्यत: राजीव गांधी को ही देती है। ऐसी स्थिति में डीपी यादव को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या प्रचार नहीं मिलता। असमंजस के दौर में डीपी यादव की मुलाकात गौरीगंज निवासी जगदीश पीयूष से हुई। पीयूष ने कुछ माह पूर्व ही श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर प्रियदर्शिनी महिला विद्यापीठ नामक एक संस्था बनायी थी। इस संस्था के लिए वे प्रदेश सरकार से १०-१५ एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। सरकार से मुफ्त में जमीन प्राप्त कर उस पर वे गुरुकुल की तरह महिला विद्यापीठ की स्थापना करना चाहते थे। पीयूष की योजना थी कि विद्यापीठ के नाम पर उन्हें काफी पैसा अनुदान के रूप में सरकार से मिल जायेगा।

डीपी यादव और जगदीश पीयूष की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मेल खा गयीं। पीयूष ने यादवजी को सुझाव दिया, "बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के बजाय गौरीगंज में बंजर पड़ी ३०-४० एकड़ जमीन पर आप अपने संस्थान की ओर से कोई प्रदर्शनी लगवाइये और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराइये। प्रधानमंत्री के नाम पर सभी सरकारी विभाग प्रदर्शनी में अपने पंडाल लगायेंगे।"

जगदीश पीयूष इसके पूर्व 'गांव में प्रेस' का एक आयोजन गौरीगंज में कर चुके थे। इस कार्यक्रम में न चाहते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरबहादुर को हेलीकाप्टर से १५-२० मिनट के लिए पहुंचना पड़ा था। वह एक बहुत छोटा कार्यक्रम था।

इसीलिए जगदीश पीयूष ने डीपी यादव को सुझाव दिया, "आप प्रदर्शनी लगवाने का इंतजाम करें। गौरीगंज में व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। अगर कहें, तो मैं कैप्टन (सतीश शर्मा) से बात कर प्रदर्शनी लगवाने की मजूरी दिला दूं।"

जगदीश पीयूष के सुझाव पर ही प्रस्तावित प्रदर्शनी का नाम 'विज्ञान गांव की ओर' रखा गया। यादव और पीयूष ने दिल्ली में कैप्टन से बात की। दोनों ने उन्हें समझाया कि राजीवजी के इक्कीसवीं सदी के सपने को साकार करने में यह प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। कम से कम अमेठी की जनता को विज्ञान और तकनीक की नवीनतम जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। एक अच्छी और उद्देश्यपूर्ण योजना जानकर कैप्टन ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसी के साथ यह तय हुआ कि प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराया जाये।

युद्धस्तरीय तैयारी: दोहरे उद्देश्य की इस योजना को अंजाम देने का कार्य बड़े जोरशोर से शुरू हुआ। प्रदर्शनी स्थल के चयन की जिम्मेदारी जगदीश पीयूष ने ले ली। आनन-फानन उन्होंने गौरीगंज कस्बे से लगभग दो किलोमीटर दूर बंजर पडी लगभग ५० बीघा जमीन ढूंढ निकाली। भूमि के स्वामी, गांववालों को यह समझाया गया कि इस जमीन को दिल्ली की एक संस्था उपजाऊ बना देगी, इसलिए फिलहाल इस बंजर जमीन को प्रदर्शनी लगाने के लिए दे दिया जाये। पहले तो गांववाले तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्हें डरा-धमका तथा प्रलोभन देकर करीब २६ एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसी जमीन से सटी करीब दो एकड जमीन सस्ते दामों पर जगदीश पीयूष ने प्रियदर्शिनी विद्यापीठ के नाम से खरीद ली। खरीदी गयी इस ज़मीन के एक भाग पर उन्होंने विद्यापीठ का कार्यालय बनवा लिया।

प्रदर्शनी के लिए जमीन की व्यवस्था हो जाने के तत्काल बाद जनवरी १९८९ में डीपी यादव की अध्यक्षता में प्रदर्शनी आयोजन समिति की एक बैठक सरकारी स्तर पर बुलायी गयी। आयोजन समिति में राष्ट्रीय बंजर भूमि और ग्रामीण विकास परिषद नयी दिल्ली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद-दिल्ली, प्रादेशिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय—नई दिल्ली, पर्यावरण संरक्षण उन्नयन और एकांतर ऊर्जा विभाग, दूर संचार विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना आयोग सहित लगभग एक सौ सरकारी विभागों को शामिल कर उन्हें अपने-अपने स्टाल इस प्रदर्शनी में लगाने का निर्देश दिया गया।

डीपी यादव का साथ देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, नयी दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक डा० रामकृष्ण आयंगर भी जोरशोर से लग गये। यही वजह थी कि प्रौद्योगिकी परिषद को प्रदर्शनी का सहसंयोजक बना दिया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दिये गये कि वे अपने-अपने स्टाल प्रदर्शनी में लगायें।

प्रदर्शनीस्थल पर सैनिटरी कार्य तथा शामियाना और बांस बल्ली लगाने का ठेका डीपी यादव ने दिल्ली के दो ठेकेदारों, बंसल एंड कंपनी और राकेश कुमार, को दे दिया। डीपी यादव और ठेकेदारों ने आपसी बातचीत में तय किया कि प्रत्येक विभाग से स्टाल लगाने और उसकी साजसज्जा के लिए दो लाख रुपए लिये जायेंगे। बंसल एंड कंपनी को सैनिटरी कार्य के लिए सात लाख रुपए का ठेका अलग से दिया गया। प्रदर्शनीस्थल तक जाने के लिए बांस-बल्ली से बनाये जानेवाले प्रत्येक स्वागत द्वार (गेट) की लागत साढ़े आठ हजार रु० निर्धारित की गयी। प्रत्येक विभाग और बैंक से कहा गया कि वे ठेकेदार राकेश कुमार के माध्यम से अपना एक-एक गेट अवश्य लगवायें और इसके लिए साढ़े आठ हजार रुपए ठेकेदार को दें।

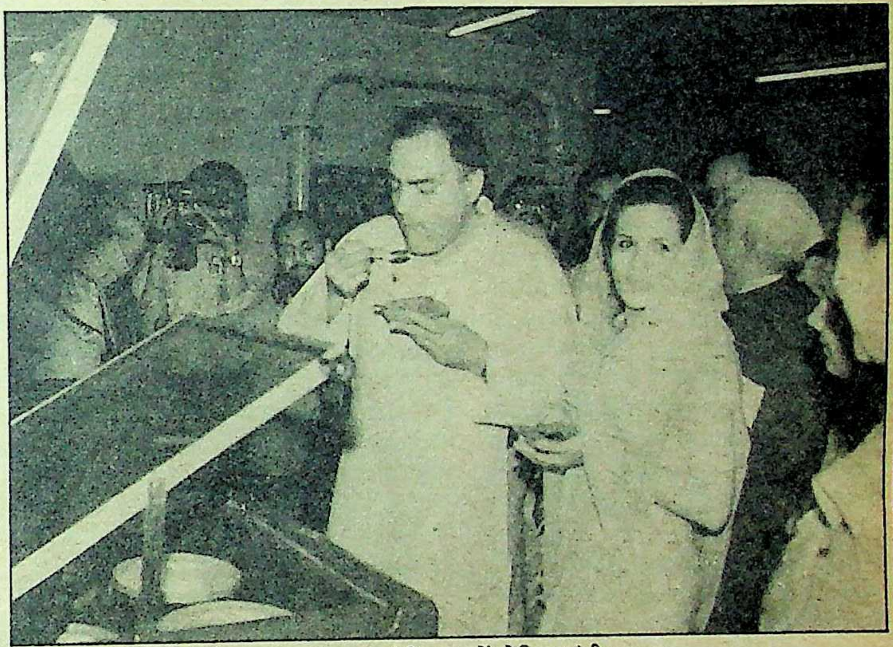

समय का स्वाद: प्रदर्शनी में जलपान करते प्रधानमंत्री, बगल में सोनिया गांधी

पूंजी की प्रगति: प्रदर्शनी में बैंक-स्टाल देखते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी

उद्घाटन प्रसंग: प्रदर्शनी के उद्घाटन की तिथि ४ मार्च निर्धारित की गयी। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी के उद्घाटन की सहमति दे दी। यह जानकारी मिलते ही कि प्रदर्शनी का उद्घाटन राजीव गांधी करेंगे, केंद्र और प्रदेश के सभी प्रमुख विभाग इस प्रदर्शनी में अपने स्टाल लगाने के लिए दौड़ पड़े। लगभग दो सौ विभागों ने अपने-अपने स्टाल लगाने की स्वीकृति

आयोजन समिति को भेज दी।

ऊसर जमीन को समतल करने, प्रदर्शनस्थल तक विद्युत पहुंचाने, सुलतानपुर-रायबरेली मार्ग से प्रदर्शनीस्थल तक जाने के लिए एक किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बनाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक किलोमीटर का संपर्क मार्ग बनाने के लिए जब किसानों की उपजाऊ भूमि पर लगी फसल बर्बाद कर दी, तो गांववालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामला पुलिस तक गया, लेकिन बड़े अफसरों की धौंस के आगे गांववालों को चुप रह जाना पड़ा। प्रदर्शनीस्थल के पास ही राज्य विद्युत परिषद ने रातदिन काम कर चार शक्तिशाली ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये, ताकि प्रदर्शनी को निर्बाध रूप से विद्युत-आपूर्ति की जा सके। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारियां पूरी हो गयीं। इसी बीच जब प्रदर्शनी के आयोजकों को यह पता चला कि प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी के उद्घाटन की अपनी पूर्वसहमति वापस ले ली है, तो आयोजकों के हाथ-पैर फूल गये। भाग दौड़ कर किसी प्रकार उन्होंने उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा को उद्घाटन के लिए तैयार किया। लेकिन ऐन मौके पर जब वे भी उद्घाटन के लिए नहीं पहुंचे, तो किसी तरह आयोजकों ने प्रदेश के राज्यपाल से ४ मार्च की शाम उद्घाटन कराया। राज्यपाल ने अस्वस्थ होने के कारण पहले तो उद्घाटन करने से इनकार कर दिया था, किंतु बाद में डीपी यादव का मन रखने के लिए वे उद्घाटन करने गये और मात्र दस मिनट रुककर वापस लौट गये।

प्रधानमंत्री से प्रदर्शनी का उद्घाटन कराने में असफल हो जाने के बावजूद आयोजकों ने हिम्मत नहीं हारी। कैप्टन सतीश शर्मा के प्रयास से प्रधानमंत्री को प्रदर्शनी में लाने के लिए ११ मार्च की तारीख तय हुई। किसी भी प्रदर्शनी के उद्घाटन और समापन-समारोह के बारे में तो प्रायः सुना जाता है। लेकिन प्रदर्शनी 'समर्पण-समारोह' का आयोजन शायद पहली बार सुना गया। यह आयोजकों के दिमाग की ही उपज थी। ११ मार्च की तारीख इसी 'समर्पण-समारोह' के लिए तय की गयी।

मुख्यमंत्री की नाराजगी: मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी इस प्रकार की प्रदर्शनी के आयोजन के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि इस प्रदर्शनी के आयोजन पर खर्च होनेवाली भारीभरकम राशि विकास कार्यों में खर्च की जाये। यही वजह थी कि प्रदर्शनी की तैयारी की रूपरेखा देखने के लिए मुख्यमंत्री एक दिन भी प्रदर्शनीस्थल पर नहीं गये, जबकि केंद्र और प्रदेश के तमाम मंत्री अपने-अपने विभाग द्वारा लगाये जा रहे पंडाल की तैयारी देखने के लिए उद्घाटन से पूर्व दर्जनों बार गये। शिक्षा, सिचाई, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, डेरी, आवास-विकास, स्वास्थ्य, खाद्य और आपूर्ति, नगर विकास, खादी-ग्रामोद्योग, जल निगम आदि विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने स्टाल सजाने में हफ्तों पहले से लगे रहे। सरकारी स्तर पर विभागों का सहयोग मिलने में कोई अड़चन न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री के सचिव एसएटी रिजवी और प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव ब्रजेश कुमार को आयोजन समिति में शामिल कर लिया गया था।

बुद्धि की उपलब्धि : जगदीश पीयूष

कहा जाता है कि प्रदर्शनी के प्रत्येक स्टाल पर कम से कम दो लाख रु० खर्च हुए। केंद्र और प्रदेश के विभिन्न विभागों, बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने प्रदर्शनी में २०४ स्टाल लगाये थे। इसके अतिरिक्त पांच हजार लोगों को बैठने के लिए पांच लाख रु० की लागत से एक विशाल पंडाल भी बनवाया गया था।

११ मार्च को प्रधानमंत्री को 'समर्पण समारोह' में आना था। खबरों के मुताबिक एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी कर दिया कि उनकी अनुमति लिए बिना राज्य का कोई भी मंत्री, प्रदर्शनी में नहीं जायेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना कर मंत्रिपरिषद के ४६ में से ४१ सदस्य ११ मार्च को प्रधानमंत्री कीं अगवानी के लिए प्रदर्शनीस्थल पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रियों में वीरबहादुर सिंह और हरिकिशन लाल भगत भी पहुंच गये थे।

चुनाव अभियान: एक तरह से यह प्रदर्शनी ग्रामीणों को विज्ञान और तकनीक की शिक्षा देने के बजाय प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए आयोजित की गयी थी। शायद इसीलिए ११ मार्च को राजीव गांधी के प्रदर्शनीस्थल से जाने के तत्काल बाद प्रदर्शनी में लगे स्टाल उखड़ने लगे। प्रदर्शनी में लगे स्टालों पर ४ करोड़ रु० जरूर खर्च हुए, घर 'विज्ञान गांव की ओर' एक कदम भी नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री ने स्वयं देखा कि कई विभागों के स्टालों में रखे कम्प्यूटर काम नहीं कर रहे थे। सौर ऊर्जा विभाग के स्टाल में रखे चूल्हे में ऊर्जा ही नहीं थी। बार-बार प्रयास के बाद भी जब अधिकारी ऊर्जा नहीं पैदा कर सके, तो प्रधानमंत्री ने मुस्कराकर कहा, "ठीक है, इसी तरह प्रयास करते रहिए, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही।" प्रदर्शनी में लगाये गये स्टालों पर ग्रामीणों को तकनीकी के बारे में न कोई बतानेवाला था और न ही ग्रामीणों की समझ में कुछ आ रहा था। हां, प्रदर्शनी के स्टालों को देखकर ग्रामीणों ने मेले का-सा मजा जरूर लिया।

प्रदर्शनी में राजीव गांधी का आगमन, क्षेत्र में चुनाव-प्रचार का शुभारंभ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजीव गांधी ने सभी सुरक्षा बंधनों को तोड़कर जिस प्रकार जगह-जगह रुककर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और देहात में जाकर लोगों का दुख-दर्द पूछा, उससे अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें अमेठी से ही चुनाव लड़ना है।

प्रदर्शनी के अंदर बने भव्य पंडाल में करीब पांच हजार लोग दोपहर से ही राजीव गांधी के दो शब्द सुनने के लिए लालायित थे। परंतु पूरी प्रदर्शनी में डेढ घंटे तक सोनिया गांधी के साथ घूमते रहने के बावजूद वे दो मिनट के लिए भी उस पंडाल में क्यों नहीं गये? यह किसी की समझ में नही आया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 'समर्पण समारोह' की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी को करनी थी, लेकिन घोषणा के मुताबिक किसी भी प्रकार का कोई समर्पण समारोह हुआ ही नही।

दावा-दर-दावा : विज्ञान प्रदर्शनी के नाम पर धन और जमीन की जो बंदरबांट हुई, उसकी चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है। जगदीश पीयूष तो अब दावे के साथ यह कह रहे हैं कि जिस ऊसर जमीन पर यह प्रदर्शनी लगी थी, वह उनकी नवगठित संस्था प्रियदर्शिनी महिला विद्यापीठ की है। यह जमीन अब न केवल विकसित हो गयी है वरन् वहां सीवर और पेयजल के पाइप तथा १५० खंभों पर लगे तारों में बिजली दौड़ रही है। इस जमीन पर अब पूरी तरह प्रियदर्शिनी महिला विद्यापीठ का कब्जा है।

दूसरी ओर सुलतानपुर के अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) सच्चिदानंद दुबे, जिन पर ५० एकड़ की इस जमीन को विकसित करने की जिम्मेदारी थी, कहते हैं, "यह जमीन गांववालों ने प्रदर्शनी लगाने के लिए दान में दी थी। मैंने सरकारी साधनों से जमीन का विकास कर दिया है। प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के बाद अब यह सुनने में आया है कि गांववालों ने वह जमीन जगदीश पीयूष को दान में दे दी है।"

इसके विपरीत अनेक ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनकी जमीन पर जोर-जबरदस्ती से कब्जा किया गया। इस बारे में जगदीश पीयूष कहते हैं, "प्रदर्शनी के आयोजन में दिल्ली के ठेकेदारों से किसी का क्या गुप्त समझौता हुआ, मुझे नहीं मालूम। प्रदर्शनीस्थल के पास की ५ बीघा जमीन गांववालों ने प्रियदर्शिनी महिला विद्यापीठ को दान में दी है। लगभग पांच बीघा जमीन मैंने पांच हजार रुपए प्रति बीघे की दर से ग्रामीणों से खरीदी है।" (जबकि उस क्षेत्र में जमीन का दाम अस्सी हजार रु० प्रति बीघे से कम नहीं है।)

पीयूष कहते हैं, "यह सारी की सारी जमीन हमारी संस्था को दान में मिल चुकी है। यह प्रदर्शनी, हमारी संस्था की जमीन पर ही लगी थी। अब संस्था के पास करीब सत्तर बीघे जमीन हो गयी है।"

बहरहाल, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ३० करोड़ रु० खर्च करके जो ड्रामा हुआ है, उससे जनता को भले ही कोई लाभ न हुआ हो, अघोषित उद्देश्य पूरा हो गया है और कुछ लोगों की प्रदर्शनी की आड़ में अच्छी खासी कमाई हो गयी है।

छाया: मनमोहन शर्मा

—गौरीगंज से अजय कुमार

“सितारे हैं अनेक, नाम सिर्फ एक-खेतान”

हेमा मालिनी, राज बब्बर, पद्मिनी, राधिका, देविका... मैगनेट, बैरॉन, टाइकून, डाइनेस्टी, मिनि, चिकि, मिकि, विकि, रूपा, सोना...हमारे सितारों की सूची काफी लम्बी है। कार्यकुशलता और सुन्दरता में सभी एक से बढ़कर एक!

हर खेतान पंखा, हमारे अपने आधुनिकतम कारखानों में निर्मित है। यानी १००% खेतान! तभी तो खेतान की उत्कृष्टता अर्थात बेजोड़ क्वालिटी भरोसेमंद है!

घर हो या दफ्तर, दुकान हो या गोदाम, बाथरूम या रसोईघर, सिनेमा हॉल या थियेटर, कारखाना अथवा फाउण्ड्री। १३५ से भी अधिक किस्मों के सीलिंग, टेबल, दीवाल, केबिन, पेडेस्टल, कूलर एग्जोस्ट, एयर सर्कुलेटर, एक्सियल फ्लो आदि पंखे विभिन्न मॉडलों, रंगों व साइजों में उपलब्ध हैं। सच तो यह है-चाहिये हवा जहाँ, खेतान है वहाँ!

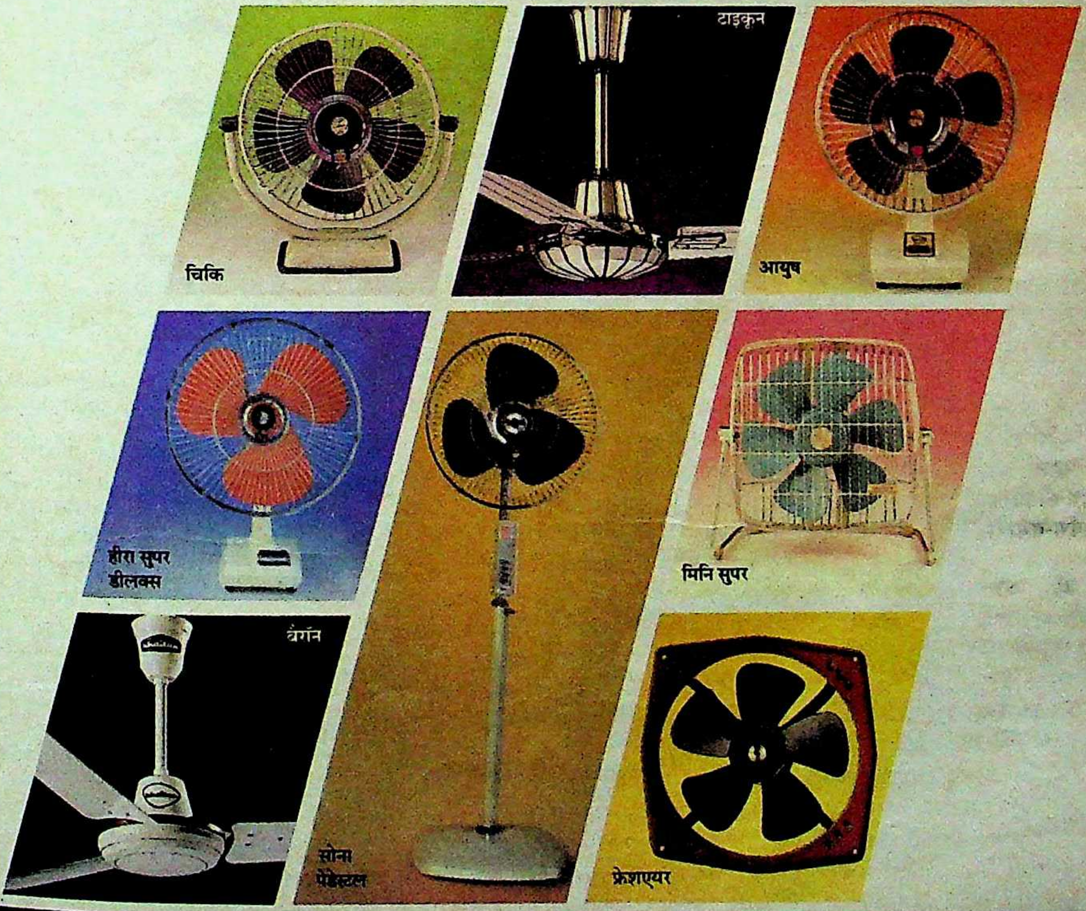
चिकि
टाइकून
आयुष
हीरा सुपर डीलक्स
मिनि सुपर
बैरॉन
सोना पेडेस्टल
फ्रेशएयर

3595 A

खेतान-सिर्फ नाम ही काफी है

'चुरहट लाटरी कांड' के अदालती फैसले के कारण मध्यप्रदेश में सत्ता-हस्तांतरण के बाद खामोशी है। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक इसे निरापद खामोशी नहीं, बल्कि तूफान से पहले का सन्नाटा मानते हैं। यदि यह बात सोलह आने सही है, तो फिर यह तूफान चुनाव से पहले केवल भोपाल की ही नहीं, दिल्ली की चूलें भी हिला सकता है। इस तूफान की आशंका इसलिए है, क्योंकि अर्जुन सिंह को जिस तरह अपदस्थ किया गया और विधायकों के बहुमत की उपेक्षा करके जिस तरह मोतीलाल वोरा को गद्दीनशीं किया गया है, उसका परवर्ती कुप्रभाव अपरिहार्य है। यद्यपि अर्जुन सिंह अपने को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही और राजीव गांधी के नेतृत्व का परमानुयायी कहते हैं, लेकिन उनके समर्थक अपने नेता की अवमानना का बदला लेने के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं। इन समर्थकों का निष्कर्ष है कि अर्जुन सिंह का सत्ता से निष्कासन दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं की बहुत पहले से चल रही मुहिम की चरम परिणति है। इन समर्थकों का इरादा इन्हीं नेताओं पर जवाबी हमला करने का है। अर्जुन सिंह के समर्थकों की 'हिट लिस्ट' में कौन लोग हैं और इन पर किस तरह के प्रहार करने की तैयारी हो रही है? यदि समय रहते इंका ने इस आशंकित गृहयुद्ध को नहीं रोका, तो इसकी परिणति क्या होगी?

अर्जुन सिंह का जवाबी हमला

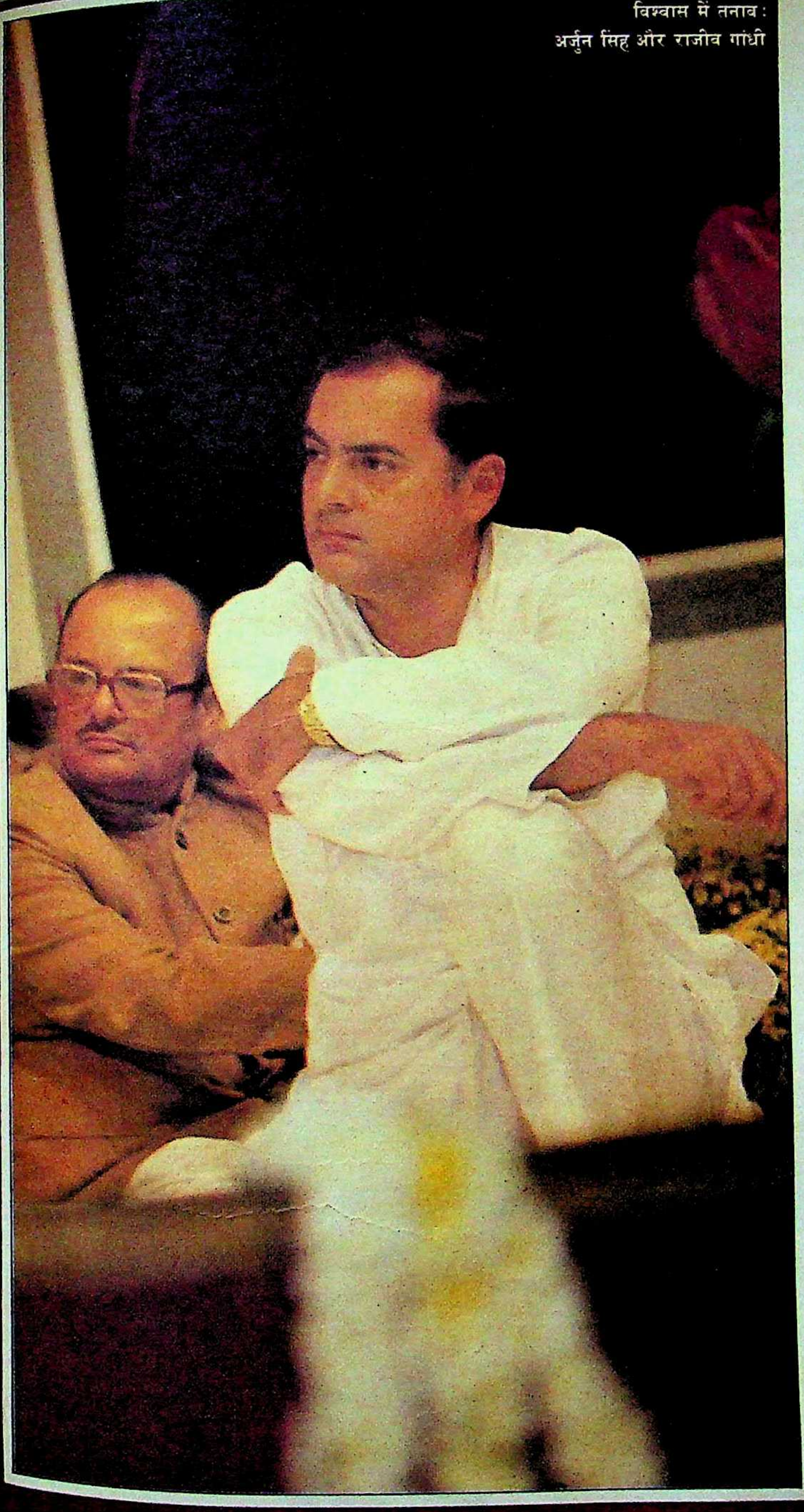

विश्वास में तनाव:
अर्जुन सिंह और राजीव गांधी

अर्जुन सिंह ने भारत में चुप्पी की राजनीति का आविष्कार किया है। राजनीति में, जहां लोगों को उनके बयानों और कर्मों से जाना जाता है, अर्जुन सिंह चुप्पी की भाषा में बोलते हैं। मौन की एक ऐसी लिपि उन्होंने ईजाद कर रखी है, जिसमें शब्द केवल अंतराल भरने के लिए आते हैं और जब वे आते हैं, तो सीधे धमाका होता है।

चुरहट लाटरी पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सिंह एकदम चुप थे। कोई बयान नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं और तो और अपने दोस्तों-समर्थकों की कोई बैठक तक नहीं। जो लोग हिंदी, अंग्रेजी और अवधी समान अधिकार से बोल सकने वाले इस राजनीतिक को करीब से जानते हैं, वे धमाके का इंतजार कर रहे थे।

आक्रामक बयान: धमाका हुआ। फैसले के तीन दिन बाद २२ जनवरी को दिल्ली से जारी पैंतीस पंक्तियों के एक बयान में सिंह ने अपनी परिचित अदा में पहले तो उस जांच का स्वागत किया जो उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की जानी थी। इसके बाद सिंह ने नापतौल कर जो लिखा, उसका सार यह था कि अगर उनके बेटे ने कुछ गलत किया हैं, तो उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए, लेकिन सिंह और उनके कैरवा बांध वाले 'कुख्यात' बंगले को चुरहट लाटरी से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर जोड़ा भी जा रहा है, तो इसके बारे में सफाई देने का मौका अदालत ने उन्हें क्यों नहीं दिया?

पाटों के बीच: मोतीलाल वोरा

छाया: रोटू

शब्दों और पंक्तियों के बीच में से पढ़ा जाये, तो असल में यह राजनीतिक रूप से आक्रामक बयान था और सिंह के तात्कालिक राजनीतिक इरादों को साफ करता था। न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि देश के प्रति सिंह का कर्तव्य है कि वे शंका और संशय को साफ करें। सिंह ने अदालत के फैसले को बयान के स्तर तक लाते हुए, बयान के जरिए ही उसका जवाब दे दिया।

हालात और मुद्राओं से साफ है कि अर्जुन सिंह अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जवाबी हमले की भूमिका बना चुके हैं और उनकी राजनीतिक हिटलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। उनके

रणनीति पर चिंतन: सिंधिया और वोरा

छाया: रोंटू

निकटतम सांसद, भूतपूर्व कलक्टर अजीत जोगी से ले कर विधायक रमाशंकर सिंह तक को जिस हड़बड़ी में गोटियां फिट करते और राजनीतिक सुरंगें बिछाते देखा जा रहा है, उससे इस 'हिटलिस्ट' के नाम भी साफ हैं और उन्हें निबटाने की प्रस्तावित शैली भी।

हिटलिस्ट: अर्जुन सिंह के समर्थक इस बात से इनकार नहीं करते कि अदालत के फैसले और प्रधानमंत्री की इच्छा का आदर करते हुए सिंह खुद ही त्यागपत्र दे देते, पर एक बड़े और अब तक साफ हो चुके षड्यंत्र के जरिए उन्हें 'हटाया गया'। हटाने की इस राजनीति में दिल्ली में बैठे जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, उनमें पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री शीला दीक्षित से लेकर प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभरे माधव राव सिंधिया और मोतीलाल वोरा भी थे। जाहिर है कि अर्जुन सिंह की हिटलिस्ट में यही लोग सबसे ऊपर होंगे। इसके अलावा सिंधिया के करीबी सांसद प्रताप भानु शर्मा, सुरेश पचौरी और रामेश्वर नीखरा को भी अर्जुन सिंह की स्वयंभू कमांडो फोर्स ने अपने हमलों के दायरे में ले लिया है। हालांकि पचौरी, सिंह-विरोधी अभियान में अपने शामिल होने से इनकार करते हैं और सबूत में बताते हैं कि कांग्रेस कार्यसमिति ने सिंह से शाम ६ बजे त्यागपत्र मांग लिया था और वे नगालैंड के चुनाव-प्रचार से उसी रात ग्यारह बजे लौटे थे। हालांकि बाद में वे सिंधिया और वोरा के साथ भोपाल गये और वहां अपनी युवक कांग्रेस के जरिए शक्ति-परीक्षण की नौबत भी ला दी—लेकिन इसके जवाब में उनके पास दबी हंसी के अलावा कुछ और नहीं है। यहीं यह याद दिलाना भी ठीक रहेगा कि प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा की सदस्यता तक पचौरी अर्जुन सिंह का ही चुनाव थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिंधिया का खेमा पकड़ लिया। वोराजी और 'महाराज' के साथ असंतुष्ट कहे जाने वाले दौरों में पचौरी और उनके शिष्य सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर हमेशा साथ रहते थे और उनके भाषणों की थीम होती थी कि प्रदेश सरकार अक्षम है, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार जायेगी। अर्जुन सिंह-समर्थक कहते हैं कि पचौरी ने डबल क्रास किया है। 'इधर' आ कर वे लगातार मिलते थे और 'उधर' जाकर खिलाफत करते थे। शायद यही कारण है कि पचौरी अर्जुन सिंह की हिटलिस्ट में हैं।

अचानक महत्वपूर्ण हो गयीं श्रीमती शीला दीक्षित की नाराजगी का कारण अर्जुन सिंह ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन उनके खासमखास सांसद अजीत जोगी फरमाते हैं कि श्रीमती दीक्षित कान्यकुब्ज राजनीति चलाना चाहती हैं और श्री श्यामाचरण शुक्ल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। पता नहीं इस बात में कितना दम है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के विश्वस्त सूत्रों ने यह पुष्टि जरूर की कि अर्जुन सिंह को पार्टी की छवि के हित में हटना ही पड़ेगा—ऐसा नोट श्रीमती दीक्षित ने फैसला आने के चार घंटे के भीतर बना कर दे दिया था। श्रीमती दीक्षित से जब इस बारे में पूछा, तो उन्होंने तमक कर कहा, "मैं रोज प्रधानमंत्री को नोट्स बना कर देती हूं और उनमें से जिस पर वे जैसा उचित समझते हैं कार्रवाई भी करते हैं। आप अकेले इस नोट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं।" श्रीमती दीक्षित का दावा है कि अर्जुन सिंह सारी असलियत जानते हैं कि मैं उनका साथ दे रही हूं या नहीं। सिंह, श्रीमती दीक्षित के इस दावे के जवाब में दबे हुए व्यंग्य भरे स्वर में कहते हैं, "उनकी मदद, सहायता और सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूं और उनको अपना धन्यवाद भी दे चुका हूं।"

श्यामाचरण शुक्ल की स्थिति: श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री भी। अपने भाई विद्याचरण शुक्ल की तरह उन्होंने कांग्रेस की दहलीज पर हार जाने के बाद विपक्ष का रास्ता नहीं पकड़ा। हालांकि कांग्रेस विभाजन के दौरान वे श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ नहीं रहे थे, उन्हें फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में उनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं हैं और इसका सबूत यह है कि १९७१ की प्रबलतम इंदिरा लहर में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा की बहुत सीटें नहीं मिली थीं। तब उन्हें हटा कर प्रकाश चंद्र सेठी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय की स्वाभाविक शत्रुता के बावजूद सेठी बाद में श्यामाचरण शुक्ल को पार्टी में वापस लाने के लिए सक्रिय हुए और उनके समर्थन ने जो भी कर सकते थे, किया। कारण साफ था—दोनों का साझा शत्रु एक था—अर्जुन सिंह। यह और बात है कि सेठी फिर इस बात को कोस रहे हैं कि अहसान मानना तो दूर,

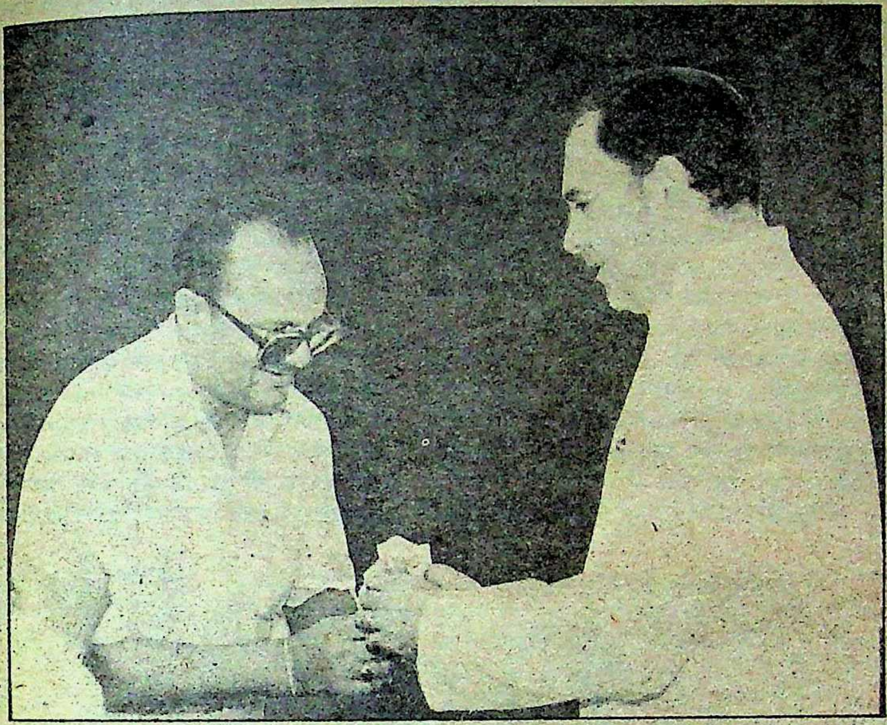

अर्जुन सिंह की हिटलिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन उनके पास उतने सैनिक नहीं हैं, जो हैं वे युद्ध के मूड में आयें—इसके लिए सिंह को अपनी शैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे। लेकिन जो हो, सिंह का पिछला रिकार्ड देखते हुए साफ है कि अपने विरोधियों को ठीक से निपटा देने की उनकी रणनीति का सामना इस बार दिल्ली से भोपाल तक बिखरे अनेक जाने-अनजाने नेताओं को करना होगा। इतना जरूर तय है कि यह लड़ाई आर-पार होगी। इस पार या उस पार!

शुक्ल उनसे मिलने तक नहीं आते। लेकिन इस आपसी मदद से सेठी-शुक्ल दोनों अर्जुन सिंह की हिटलस्ट में आ गये हैं। देखना यह है कि सहारे के लिए खुद दीवार से चिपके हुए अर्जुन सिंह इन दोनों का क्या बिगाड़ पाते हैं? अभी तो वे हमले की नहीं, आत्मरक्षा की मुद्रा में हैं।

लेकिन सिंह के सिपहसालार खामोश नहीं हैं। माधव राव सिंधिया से अपनी राजनीतिक शत्रुता को समाजवादी मतभेद कहनेवाले राजनारायण के भूतपूर्व शिष्य, जनता सरकार में मंत्री रहने के बाद अब कांग्रेस विधायक रमाशंकर सिंह पर सिंह के जमाने में समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगता रहा है। श्यामाचरण शुक्ल के बारे में रमाशंकर सिंह कहते हैं, "उन्हें पार्टी में वापस लाकर राजीवजी ने जरूर कोई रास्ता निकाला होगा। लेकिन अगर वे पार्टी के लिए इतने ही काम की चीज होते, तो उन्हें प्राथमिक सदस्यता तक ही सीमित क्यों रखा जाता?" लेकिन तमाम 'समाजवादी मतभेदों' के बावजूद रमाशंकर सिंह माधव राव सिंधिया के बारे में साफ-साफ कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं, "कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं और उसे साबित भी कर सकता हूं, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो करना है, जनता ही करे। जनता सब देखती है"—और रमाशंकर सिंह एक प्रसिद्ध फिल्मी गाना गुनगुनाने लगते हैं, "ये जो पब्लिक है—सब जानती है।"

अरुण नेहरू का अभियान : अर्जुन सिंह की हिटलिस्ट में कांग्रेस से बाहर का एक बड़ा नाम है और उस पर उनका आरोप है कि वह नेता कांग्रेस वालों में टक्कर पैदा करवा कर राजीव गांधी को कमजोर करना चाहता है। नेता का नाम है अरुण नेहरू और अर्जुन सिंह-समर्थकों का आरोप है कि अरुण नेहरू विद्याचरण शुक्ल के जरिए—श्यामाचरण शुक्ल को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि पार्टी में उनकी और विद्याचरणजी की वापसी का रास्ता साफ हो सके। इन अरुण नेहरू-शुक्ल विरोधियों का आरोप है कि अरुण नेहरू श्यामाचरण शुक्ल से मालचा मार्ग, दिल्ली की एक कोठी में अकसर मिलते रहे हैं। जो हो, श्यामाचरण शुक्ल को पार्टी में कोई बड़ा पद चाहे न मिला हो, पर उनका आना-जाना महत्वपूर्ण लोगों के यहां है। इन महत्वपूर्ण लोगों में कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद भी हैं और गृहमंत्री बूटा सिंह भी। प्रसंगवश, यही दोनों नेता मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह का तख्ता उलटने के लिए गये थे। शुक्ल चुरहट लाटरी के फैसले की प्रतियां लगातार पत्रकारों में बांटते देखे गये थे।

बूटा सिंह-गुलाम नबी की खुंदक : बूटा सिंह और गुलाम नबी आजाद अर्जुन सिंह से इतना क्यों दुखी हैं—यह जानना भी जरूरी ही है। बूटा सिंह पंजाब की राजनीति में कांग्रेसी संत लोंगोवाल की छवि बनाना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि पंजाब में अगर कोई समझौता हो, तो उनके बताये लोगों के साथ हो। डाकू मलखान सिंह से लेकर संत लोंगोवाल तक का हृदय परिवर्तन कराने में उस्ताद अर्जुन सिंह ने बूटा सिंह को कोई घास नहीं डाली और उसका नतीजा दक्षिण दिल्ली चुनाव में मिले सिख-विरोध से भुगता। इसके बाद सिंह और उनके २१ समर्थकों के नाम गृहमंत्रालय की विभिन्न जांचों में आये और ज्यादातर जांचें अभी लटकी ही हुई हैं।

गुलाम नबी आजाद, सिंह से तब से दुखी हैं, जब सिंह पार्टी के सर्वशक्तिमान उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय आजाद की दी हुई पदाधिकारियों की सूची, उन व्यक्तियों के रिकार्ड की जांच कराने के बाद रद्द कर दी गयीं और पदाधिकारियों का चयन पता नहीं किसकी राय से किया गया। आजाद ने भोपाल में अर्जुन सिंह के स्थान पर मोतीलाल वोरा को नया नेता चुनवा कर दिल्ली आने के बाद राजीव गांधी को जो रिपोर्ट दी है, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अर्जुन सिंह की सहमति और उपस्थिति में कांग्रेस विधायकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आजाद को चमचा कहा, तो एक और विधायक ने पूछ डाला कि पूरे जीवन में, कुल मिलाकर आजाद को जितने वोट नहीं मिले होंगे, उससे ज्यादा वह (विधायक) एक बार में पा चुका है। आजाद ने प्रधानमंत्री को क्या रपट दी, इसकी जानकारी पत्रकारों और संबंधित नेताओं को कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने दी है।

केसरी, अर्जुन सिंह के कभी पक्ष में जाते हैं, तो कभी खिलाफत करने में लगते हैं। केसरी और सिंह दोनों के यहां आने-जानेवाले बिहार युवा कांग्रेस के नेता एके सिंह के अनुसार सिंह ने पार्टी

उपाध्यक्ष रहते हुए पार्टी के खजाने की जांच के आदेश दिये थे। इसी से केसरी नाराज हैं। विश्वस्त कांग्रेसी सूत्रों के अनुसार पार्टी के भीतर से ही यह मांग भी की जाने वाली है कि पार्टी की ओर से निकाले जानेवाले साप्ताहिक हिंदी और अंग्रेजी 'कांग्रेस' के हिसाब की भी जांच की जाये। इन दोनों साप्ताहिकों के कर्ताधर्ता गुलाम नबी आजाद हैं, जो विडंबनापूर्वक कांग्रेस मुख्यालय २४, अकबर रोड के उसी कमरे में बैठते हैं, जहां पार्टी उपाध्यक्ष की हैसियत से अर्जुन सिंह बैठा करते थे।

जवाबी हमले के तौर पर ही पार्टी के बोगस सदस्यतावाले मसले को फिर से जीवित करने का इरादा अर्जुन सिंह के शुभचिंतक दिखा रहे हैं। इस मामले में सबसे सीधे आरोप और संदेह सीताराम केसरी पर ही हैं। यों भी बोगस सदस्यता के मुद्दे की जांच के लिए पार्टी की जो समिति बनी थी, उसको पता नहीं क्यों एकदम अप्रासंगिक करार दे दिया गया है। उसका जिक्र तक कोई नहीं करता। पार्टी सूत्रों के अनुसार फर्जी सदस्य बनाने की सर्वाधिक शिकायतें उस समय जम्मू कश्मीर से आयी थीं, जब गुलाम नबी आजाद वहां सदस्यता-अभियान के कर्ताधर्ता थे। सदस्यता-अभियान के कश्मीर में अग्रणी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद तो अब जनमोर्चा में हैं, इसलिए कांग्रेस की फर्जी या असली सदस्यता उनकी बला से। यहां यह भी याद किया जा सकता है कि फर्जी सदस्यता की जांच के आदेश भी अर्जुन सिंह ने ही दिये थे और शिकायतें मध्य प्रदेश से भी कम नहीं थी।

आदिम रहस्य: रहस्यों की सृष्टि के लिए विख्यात अर्जुन सिंह के लिए भी मोतीलाल वोरा एक आदिम रहस्य बने रहेंगे। यह विडंबना ही है कि जिस शपथ पत्र के आधार पर चुरहट लाटरी का कुख्यात फैसला हुआ, वह वोरा का ही दिया हुआ था और उसमें उन्होंने चुरहट चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट लाटरी को निजी और एकदम गैरसरकारी बतलाया था। २२ नवंबर, १९८८ को दिया गया यह शपथ पत्र २६ जुलाई, १९८५ को मध्य प्रदेश विधानसभा में दिये गये उनके बयान के खिलाफ था। विधानसभा में वोरा ने कहा था कि चुरहट लाटरी प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत लाटरी थी और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गयी। उच्च न्यायालय ने शपथ पत्र को सरकार द्वारा दी गयी अधिकृत जानकारी मानते हुए फैसला दिया।

शपथ पत्र और विधानसभा के बयान के बारे में अंतर्विरोध के सवाल पर वोरा से जनसंपर्क किया गया, तब उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। वे बोले कि मैंने वह शपथ पत्र याद्दाश्त के आधार पर दिया था। उन्होंने अर्जुन सिंह तक यह संदेश भी भिजवाया कि प्रदेश के एडवोकेट जनरल अगर उनसे मिलकर 'चर्चा' कर लेते, तो शपथ पत्र में दिये गये विवरणों में सावधानी बरती जाती। अर्जुन सिंह ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि वोरा ने उनसे फैसला आने के बाद ऐसा कहा भी था, लेकिन वे अगर चाहते और समय पर सूचित करते, तो सारे सरकारी रिकार्ड उन्हें उपलब्ध करा दिये जाते। फैसला आने के बाद 'अगर और इसलिए' की भाषा में बोलना कोई ठीक बात नहीं है।

वोरा ने पाला बदला: अर्जुन सिंह को वोरा का काम और उनकी कार्यशैली विश्वासघात के आसपास ही लगती है। तभी, मध्यस्थों की लाख कोशिश के बावजूद इस्तीफे के पहले वे वोरा से मिलने को तैयार नहीं हुए। बाद में भी वोरा और सिंह के बीच वैसी कोई विधिवत मुलाकात नहीं हुई जो एक भूतपूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच होती है। यह जानना एक उत्सुक बेचैनी का विषय हो सकता है कि अपना सरकारी विमान भोपाल भेज कर, अपने बेटे राहुल सिंह के साथ वोरा को प्रधानमंत्री से भेंट के लिए बुलानेवाले सिंह से वोरा दूर क्यों होते गये ? यह कोई रहस्य नहीं है कि वोरा के भोपाल की सबसे ऊंची प्रशासनिक गद्दी पर बैठने के बावजूद उस समय असल में मध्य प्रदेश की व्यावहारिक और वास्तविक राजधानी चंडीगढ़ थी, जहां अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। बाद में यह राजधानी ग्वालियर के जयविलास पैलेस और दिल्ली के रेल भवन चली गयी और वहां से माधवराव सिंधिया का कठपुतली राज चलने लगा।

रिश्तों के इस संक्रमण के पीछे वोराजी के समर्थक जो किस्से बताते हैं और जिनमें दम भी लगता है—वे राहुल सिंह की राजनीतिक दादागीरी के हैं जो वोरा की सरकार को अपने पिता की जगह चलाना चाहते थे। इस सिलसिले में कई वाद-विवादों और झगड़ों की सूचना वोराजी के समर्थकों ने दी, जिनमें से ज्यादातर तबादलों से संबंधित मामलों पर हुए बताये गये। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मसले पर भी विवाद होता ही रहा, जिसमें अंततः राहुल सिंह को हार जाना पड़ा। जीत सुरेश पचौरी की हुई, जिन्होंने अपने शिष्य सुरेंद्र सिंह ठाकुर को पहले प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष और

पुत्र कोप: अर्जुन सिंह और अजय सिंह

बेटों की राजनीति

बेटों की राजनीति मध्य प्रदेश में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी हरियाणा में चौटाला बंधुओं की टकराती हुई राजनीति। असल में यह राजनीति कांग्रेस या विपक्ष से उतना संबंध नहीं रखती, जितना सत्ता के समीकरण से। यह बेटों की उतनी नहीं, जितनी सत्ता की राजनीति है।

बात मध्य प्रदेश की हो रही है, जहां चार बेटे अपने पिताओं का राजनीतिक उत्तराधिकार पाने की लड़ाई में शामिल हैं। इनमें से राजनीतिक क्षेत्रों में केवल एक को ही पिता का सीधा और सपाट आशीर्वाद प्राप्त है और वे हैं अर्जुन सिंह के पुत्र राहुल सिंह। उनका नाम अजय सिंह है और वे अपने पिता द्वारा विकसित किये गये चुनाव क्षेत्र चुरहट के विधायक हैं।

अर्जुन सिंह के आसपास और उनके दरबार के नवरत्नों में से भी कई का कहना है कि अपने बेटे की राजनीति को बढ़ाने के मोह में फंस कर सिंह ने खुद अपनी राजनीति का कबाड़ा कर लिया। और-तो-और प्रतिपक्ष के नेता सुंदर लाल पटवा का तो यहां तक कहना है, "पहले अर्जुन सिंह अपने पिता (जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गये और वहीं उनकी मृत्यु हो गयी) की छाया से ग्रस्त रहे और अब पुत्र-ग्रहण ने उन्हें अंधेरे में पटक रखा है।" विपक्ष और कांग्रेस के असंतुष्ट राहुल सिंह पर अपने पिता के मुख्यमंत्रित्व में समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाते रहे हैं और यह आरोप एकदम निराधार लगता हो, ऐसा भी नहीं है। और-तो-और अभी पिछले दिनों, पिछले दरवाजे से समाचार पत्र मालिक बनने की भी उनकी कामना तब प्रकट हुई, जब चुरहट लाटरी के अपने दोस्त ब्रजेश निगम से 'ब्रह्मवाक्य' नाम का एक साप्ताहिक उन्होंने निकलवाया और बगैर बिक्री के भी इस अखबार को सरकारी विज्ञापनों का सा संरक्षण मिला। यह अखबार हर अंक में अर्जुन सिंह की तस्वीर छापता रहा है। राहुल (अजय) सिंह, अर्जुन सिंह के छोटे बेटे हैं। उनके बड़े सुपुत्र अभिमन्यु दक्षिण भारत की एक बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर

बाद में कप्तान सतीश शर्मा की मदद से संसद सदस्य भी बनवा दिया। पचौरी तब तक तंबू बदल चुके थे। अर्जुन सिंह के हमलावर दस्ते की हिटलिस्ट में वोरा और सिंधिया के अलावा जो नाम सबसे ऊपर हैं, उनमें पचौरी भी हैं।

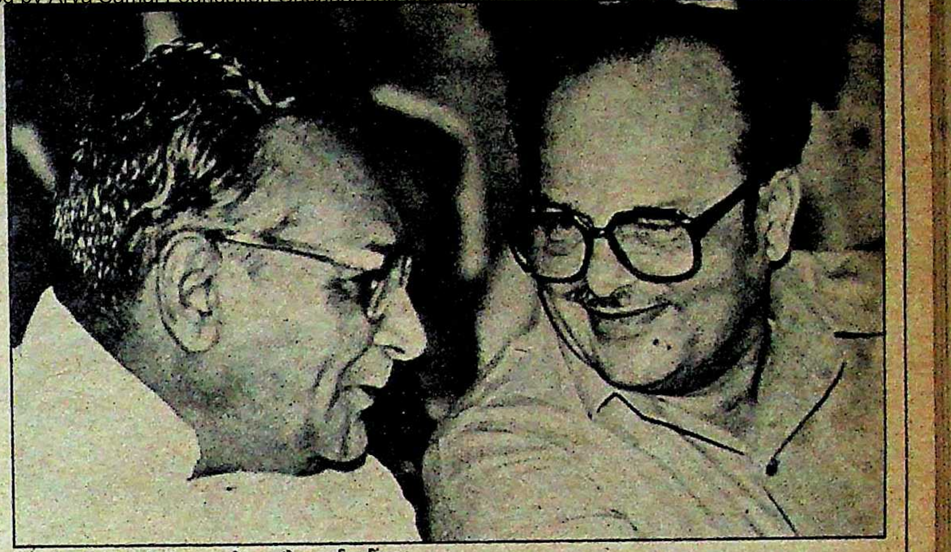

आमने-सामने : मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह

वोरा से विफल संधि : बीच-बीच में कई बार लगा कि अर्जुन सिंह के सिंधिया से बैर के बावजूद वोरा और अर्जुन सिंह एक साथ आ रहे हैं। दोनों ने एक साथ कई यात्रा-कार्यक्रम भी बनाये और प्रधानमंत्री से एक साझा और स्वाभाविक रूप से गोपनीय मुलाकात भी की। पिछले साल अक्तूबर के पहले सप्ताह में हुई इस मुलाकात में वोरा और सिंह दोनों खुद अपनी पहल पर शामिल थे। प्रधानमंत्री से यह मुलाकात वोरा-सिंह सुलह के लिए फलदायी नहीं हो सकी और इसका सीधा कारण दोनों नेताओं के अनुयायियों की चरम सीमा पर पहुंच चुकी लड़ाई थी। इसके अलावा सहकारिता चुनावों में प्रदेश एपेक्स सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष यादव से सिंह द्वारा करायी गयी कथित धांधलियों से वोरा बहुत नाखुश थे और हैं, क्योंकि कांग्रेस में अपना सहकारी आधार बनाने की उनकी कोशिशों का एकदम सत्यानाश हो रहा था। शायद इसीलिए अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में दुर्ग के अपने घर में उन्होंने श्यामाचरण शुक्ल को भोजन पर बुलाया और रणनीति तय की। इसी रणनीति का नतीजा था कि जनवरी में शुक्ल और सिंह के बीच बयानों का युद्ध चला, जिसमें शुक्ल ने सिंह-सरकार को निकम्मा कहा और सिंह ने शुक्ल को उनकी औकात याद दिलायी और संयम बरतने की सलाह, वह भी अखबारों के जरिए दी।

सिंह और उनके समर्थक समुदाय का जवाबी अभियान उन्हीं दिनों सबसे ज्यादा तेज हुआ। बीस सूत्री कार्यक्रम सलाहकर समितियों से वोरा-सिंधिया समर्थक कथित आपराधिक अतीत के आधार पर हटाये जाने लगे। वोरा खेमा भी चुप नहीं रहा। सिंह के दरबार में हाजिरी बजाकर, कई मंत्रियों से चरित्र प्रमाणपत्र ले लेनेवाली सावित्री अग्रवाल को वेश्यावृत्ति के आरोप में पकड़ा गया और इस मामले के दस्तावेज मंत्रियों के चरित्र प्रमाणपत्र सहित ऊपर तक पहुंचाये गये। यह भी बताया गया कि ग्वालियर क्षेत्र में सहकारी आंदोलन के सर्वेसर्वा और मिनी मुख्यमंत्री के नाम से विख्यात यादव को एक बार पुलिस गधे पर बिठा कर भी घुमा चुकी है। यादव इस आरोप पर आग लगने की हद तक बौखलाए हुए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी ताकत से कुछ भी कर ले—अदालत में सच ही जीतता है और पुलिस को मेरे खिलाफ मामला अदालत में बेनकाब हो गया। यहां दो दिलचस्प संयोग भी हैं—एक तो यादव को गधे की सवारी करानेवाले तत्कालीन एसपी अयोध्या नाथ पाठक, तब भी और बाद में माधवराव सिंधिया के सबसे विश्वस्त अधिकारियों में से एक रहे हैं। अब वे पुलिस महानिरीक्षक हो गये हैं। संभवतः इसीलिए

हैं। राजनीतिक दायरे में वे सिर्फ तभी दिखायी दिये थे, जब उनके पिता दक्षिणी दिल्ली का निर्णायक उपचुनाव लड़ रहे थे और अभिमन्यु सिंह ने पृष्ठभूमि से चुनाव नीति का संचालन किया था।

लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक संतानों में केवल राहुल सिंह ही नहीं हैं। दो बार मुख्यमंत्री रह कर तीसरी बार बनने की कमस खानेवाले श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र अमितेश शुक्ल कई बार अपने पिता से भी ज्यादा चतुर और महत्वाकांक्षी नजर आते हैं। एक जमाने में अपने इलाके के दुर्ग शहर में दौरा करने गये कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राजीव गांधी को काले झंडे दिखाने वाले अमितेश अब प्रधानमंत्री के प्रातःकालीन दर्शनों में लगातार नजर आते हैं। हाल में उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस भी बुला रखी थी, जिसे अंतिम समय पर रात्रिभोज में परिवर्तित करके टाल दिया गया। मध्य प्रदेश के नेतापुत्रों में अखबारों का मोह कुछ ज्यादा ही है या वे पत्रकारिता के जरिए राजनीति करने के लिए सदा-उत्सुक रहते हैं। अमितेश शुक्ल भी इस झमेले से अलग नहीं हैं। वे रायपुर से प्रकाशित होनेवाले हिंदी दैनिक 'महाकौशल' के कर्ताधर्ता हैं। इस अखबार में छपनेवाली खबरों और संपादकीयों से लोग अंदाजा लगाते हैं कि श्यामाचरण शुक्ल का राजनीतिक वर्तमान क्या है और भविष्य में वे क्या गुल खिलानेवाले हैं?

अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे गायछाप छविवाले माने जाते हैं मोतीलाल वोरा। बस के परिचालक से जीवन शुरू करके 'नवभारत टाइम्स' के अंशकालिक संवाददाता २२ साल रहने के बाद वोरा का राजनीतिक भाग्योदय हुआ। इस भाग्योदय के साथ-साथ उनका पारिवारिक सितारा भी उभरता दिखायी देने लगा। उनके सुपुत्र अरुण वोरा ठीक-ठीक शब्दों में अपने पिता की राजनीतिक-दशा और दिशा तो तय नहीं करते, लेकिन उन्हीं की कृपा पर उन्हें दुर्ग जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अरुण वोरा के दुर्भाग्य से उनके पिता को अपनी ही खाली की गयी दुर्ग विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव लडना पड़ेगा, वरना अरुण वहां से विधायक बनने की तैयारी कर ही चुके थे। इन दिनों अरुण वोरा अपने पारिवारिक दैनिक 'अमृतसंदेश' और पारिवारिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंतजाम में लगे हैं और पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं। दुर्ग से विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गयी है और इसीलिए अरुण वोरा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकें बुला रहे हैं।

बेटों की इस सूची में सबसे नाजुक मिजाज नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। महाराज सिंधिया के १६ साल के इस बेटे के राजनीति में आने का पहले किसी को इलाहाम भी नहीं था, लेकिन चार साल पहले अपने पिता के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव में मंचों से काफी सधे हुए भाषण देते हुए ज्योतिरादित्य को देख कर माधवराव के इकलौते बेटे के आगे बढ़ने का अंदाजा सबको हो गया था। अब ज्योतिरादित्य हालांकि पढ़ दिल्ली में रहे हैं, पर असल में अपने पिता के राजनीतिक कामकाज में उनका प्रशिक्षणार्थी की हैसियत से काफी दखल है।

◆

साक्षात्कार/ अर्जुन सिंह

मैं पार्टी में एक ही व्यक्ति को जानता और मानता हूं —वे हैं राजीव गांधी

"मैंने राजनीति में या जीवन में कभी किसी से बदला नहीं लिया। लेकिन मेरा अनुभव यही है कि जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसका भी कभी भला नहीं हुआ"—अर्जुन सिंह कहते हैं। दिल्ली के पांच तुगलक रोड के उनके बंगले में तूफान के बाद की शांति रहती है और मुलाकातियों की सूची में अब केवल मित्रों के नाम रह गये हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह मित्र-सूची अब भी काफी लंबी है और उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री तक हैं। दरवाजे की गारद से मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस की गारद हटा ली गयी है और उसकी जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्टेनगनों ने ले ली है—यह याद दिलाने के लिए कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के अलावा यह पंजाब के पिछले राज्यपाल का भी घर है।

किताबों से भरी बैठक से कुछ चीजें गायब भी हो गयी हैं, जैसे ताजा खबरें देनेवाला टैलीकास्ट सर्विस का उपकरण और बाहर रखी प्रदेश सरकार की फोटोस्टेट मशीन। अगर गायब नहीं हुई है, तो अर्जुन सिंह की सनातन रहस्यमय मुस्कराहट—जो अब कभी-कभी सधे हुए ठहाकों में भी बिखर पड़ती है। पद से हटने के बाद का तात्कालिक अवसाद—अब गायब हो गया है। एक राजनीतिक खेल का पहला हिस्सा बुरी तरह हार जाने के बाद हुई लंबी और दोटूक बातचीत के कुछ हिस्से :

माया: इस समय आपके राजनीतिक जीवन का सबसे अवसादपूर्ण हिस्सा चल रहा है...

अर्जुन सिंह: *अब अवसाद तो नहीं है, थोड़ा दुख है और वह भी इस बात का कि मुझे राजीवजी के खिलाफ चल रही मुहिम में मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है।*

माया: यह कोशिश पार्टी के भीतर से चल रही है या बाहर से?

सिंह: *पार्टी के भीतर जो कोई राजीवजी को खतम करने की कोशिश में शामिल होगा, वह आत्महत्या का प्रयास ही करेगा। क्योंकि वह जहां है, वहां राजीवजी की वजह से ही है। बाकी सही बात तो यह है कि पार्टी के भीतर से ऐसी कोशिश करनेवालों के बारे में मुझे खुद कोई विश्वास नहीं होता! सिर्फ परिस्थितिजन्य प्रमाणों पर विश्वास करना पड़ता है। मेरी सारी चिंता यह है कि राजीवजी हैं, तो कांग्रेस है।*

माया: आप एक चुके हुए व्यक्ति की भाषा नहीं बोल रहे हैं?

सिंह: *मैं अपनी वही भाषा बोल रहा हूं जो हमेशा बोलता आया हूं। अगर आपको यह चुके हुए व्यक्ति की भाषा लगती है, तो यह आपका नजरिया है। मेरे सारे कांग्रेसी साथी यही भाषा बोलते हैं।*

माया: अच्छा, एक बात बताइए। पहली बार जब आपने मोती लाल वोरा का नाम मुख्यमंत्री-पद के लिए दिया था, तब क्या आपको यह उम्मीद थी कि वे बाद में 'विश्वासघात' करेंगे?

सिंह: *पहली बात तो यह कि मैं नहीं मानता कि वोराजी ने कोई विश्वासघात किया है। जिनका उन पर विश्वास है और जिस लिए है, उसे वे पूरा करते ही हैं। रही बात मुख्यमंत्री-पद पर उनके चुनाव की, तो वह हाईकमान का ही चुनाव था।*

माया: यह नितांत राजनीतिक जवाब है। हाईकमान को सपना तो नहीं आ रहा था कि वोराजी मुख्यमंत्री-पद के लिए उपयुक्त हैं। या आप यह कहना चाहते हैं कि वोराजी को आपसे पूछे बगैर मुख्यमंत्री बना दिया गया?

सिंह: *आप मुझे संकट में क्यों डाल रहे हैं? वोराजी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्रिमंडल में रह चुके थे और सबसे बड़ी बात यह कि विधायक थे। वरिष्ठ नेताओं में कोई विधायक नहीं था, इसलिए उनका ही नाम लेना स्वाभाविक था।*

माया: लेकिन जब आप दुबारा मुख्यमंत्री बने, तब विधायक नहीं थे और इस बार भी वोराजी विधायक नहीं हैं। इसे आप किस परंपरा में रखेंगे?

सिंह: *(चुप्पी)।*

माया: आपने और अन्य विधायकों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया?

सिंह: *(चुप्पी ..ठंडी सास) विरोध का सवाल ही कहां उठता है?*

माया: विरोध नहीं था, तो नेता चुनने में इतनी देरी क्यों हुई और मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में इतने उग्र शक्ति-प्रदर्शन की नौबत क्यों आयी?

सिंह: *शक्ति-प्रदर्शन की तो कोई बात नहीं थी। जब विधायक मंडल का नेता चुना जाता है, तो सबके मत लिए जाते हैं और यह कतई जरूरी नहीं है कि सब एक मत के हों।*

माया: क्या खुद माधव राव सिंधिया इस दौड़ में नहीं थे?

सिंह: *कुछ विधायकों ने उनके नाम का प्रस्ताव जरूर किया था।*

माया: और उन्होंने सहमति जतायी थी?

सिंह: *(चुप्पी)...वे कुछ बोले नहीं थे।*

माया: माधव राव सिंधिया आपसे इतने नाराज क्यों हैं? और मैं आपसे यह जवाब नहीं सुनना चाहता कि यह मैं सिंधिया से ही पूछूं।

सिंह: *आप मेरा जवाब तय मत करिए। लेकिन मुझे खुद उन्होंने जो एक-दो बार कहा, वह यही था कि मैंने उनके विधायक पद से उम्मीदवारों के कुछ नाम कटवा दिये। अब मैंने उन्हें लाख समझाया कि किसी की भी पूरी सूची मंजूर नहीं होती। मैं खुद मुख्यमंत्री की हैसियत से कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में तब मौजूद था। वहां बहुत सारे आधारों पर फैसले किये जाते हैं और यह हो नहीं सकता कि एक ही सूची को अंतिम स्वीकृति दी जाये। इसके अलावा और कोई कारण तो मेरी समझ में नहीं आता।*

माया: आपके विश्वस्त विधायक रमाशंकर सिंह माधव राव सिंधिया के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं।

सिंह: *मैंने रमाशंकरजी को कई बार कहा कि यह गलत है।*

माया: तो वे आपकी बात नहीं मानते? आप ही उन्हें लोकदल से कांग्रेस में लाये थे।

सिंह: अब वे क्या करते हैं, इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। श्री सिंधिया की बेटी की शादी में उन्होंने जो प्रचार किया, उसे मैंने हमेशा नापसंद किया और कहा भी। मानना-न-मानना उनके हाथ में है और अगर उन्होंने कोई अनुशासनहीनता की हो, तो श्री सिंधिया हाईकमान से उसके बारे में बात करने के लिए आजाद हैं।

माया: आपको अपने राजनीतिक जीवन में कभी विश्वासघात का सामना करना पड़ा?

सिंह: विश्वासघात तो असल में भाई साहब, बहुत सापेक्ष शब्द है। लेकिन राजनीति में यह सब होता रहता है कि आप किसी से कुछ उम्मीद करें और वह पूरी न हो या किसी पर विश्वास करें और वह अकारण उसे तोड़ दे। राजनीति में मुझे नीचा पहले भी देखना पड़ा। १९६६ में तो चुनाव ही हार गया था। १९६७ में दूसरे चुनाव क्षेत्र से लड़ा, तो उसके बाद द्वारकाप्रसाद मिश्र की सरकार ही गिर गयी। १९६७ में राष्ट्रपति चुनाव (वीवी गिरि—संजीव रेड्डी) वाले मामले में भी तनाव रहा। लेकिन आपको एक बात बताता हूं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। १९७१ में इंदिराजी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया था। मैं तैयारी कर रहा था, तो पता लगा कि प्रजा समाजवादी पार्टी से हाल में आये केशव प्रसाद सिंह को वह टिकट दे दिया गया।

माया: इसके पीछे कौन था?

सिंह: अब जितना मुझे पता है, उसके अनुसार बाबू जगजीवन राम, विद्याचरणजी और श्यामाचरणजी ने ही यह सलाह दी थी।

माया: क्या यही कारण है कि इस बार आप शुक्ल बंधुओं के गढ़ छत्तीसगढ़ के खरसिया चुनाव क्षेत्र से लड़ने पहुंचे?

सिंह: देखिए, पहली बात तो यह है कि गढ़ जैसी किसी धारणा को मैं मानता ही नहीं। पूरा प्रदेश था, मैं कहीं से भी लड़ सकता था। खरसिया से लड़ा, तो इसके पीछे किसी के प्रति कोई चुनौती नहीं थी। थी तो विपक्ष की थी और कांग्रेस कार्यकर्ता की जीत हुई।

माया: राजनीतिक विश्वासघात की बात पर याद आया, क्या आप कुछ नाम दे सकते हैं, जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा हो?

सिंह: कुछ लोग हैं जो राजनीति में विश्वासघात को अनिवार्य मानते हैं। नाम गिनाने से कोई लाभ नहीं। मैं प्रतिशोध में विश्वास नहीं करता, पर यह अवश्य है कि मुझसे जिन लोगों ने विश्वासघात किया—समय ने उन्हें अपने आप खतम कर दिया। प्रतिशोध की भावना न होना मेरी कमजोरी ही है।

माया: जैसे?

सिंह:-नाम चाहते हैं? (सोचते हुए) अरुण नेहरू थे। अब आज वे जहां हैं वहां भी इनकी कोई सुन नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में श्रीनिवास तिवारी, केपी सिंह और सीपी तिवारी हैं। आज वे कहा हैं, कोई नहीं जानता।

माया: इस सूची में वोराजी नहीं हैं?

सिंह: मैंने ऐसी कोई सूची बना नहीं रखी है। हां, मेरे साथी बार-बार मुझे यह विश्वास करने पर मजबूर करते हैं कि मैंने वोराजी पर विश्वास करके गलत किया। बीच-बीच में कुछ अवसर आये भी, जब मुझे इस बात पर गंभीरता से सोचना पड़ा। मैं मन से कामना करता हूं कि मेरा यह सोचना गलत हो।

पार्टी के भीतर जो कोई
राजीवजी को खतम करने की कोशिश
में शामिल होगा, वह आत्महत्या का
प्रयास ही करेगा।

माया: माधवराव सिंधिया के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन पर क्या इसलिए कार्रवाई नहीं की गयी कि वे बहुत पहुंच वाले आदमी हैं?

सिंह: अब यह तो संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री हर थाने में दर्ज हर एफआईआर को देखे। मेरे कार्यकाल में केवल एक ही मामला दर्ज हुआ। वह श्रीमती विजयाराजे सिंधिया के सचिव सरदार आंग्रे ने करवाया था। यह उनका पारिवारिक विवाद है, यह तो सभी जानते हैं। मैंने कभी कानून की सीमा से बाहर जाकर समझौता नहीं किया। बाकी एक जो रेल पटरी वाला मामला है, उसमें तो रेलवे से उनका समझौता ही हो गया है।

माया: भारतीय जनता पार्टी ने माधव राव सिंधिया के किसी भी मामले में कोई राजनीतिक दिलचस्पी नहीं दिखायी। उन्होंने आपके खिलाफ जो मामला दायर किया, उसका लाभ भी घूम फिर कर सिंधिया को ही मिला। आपको इस सबमें कोई पारस्परिक सहमति की गंध आती है?

सिंह: श्री सिंधिया को या खुद मुझे क्या लाभ, हानि होती है, इसकी मुझे परवाह नहीं। लेकिन अब अगर यह धारणा बन रही है कि श्री सिंधिया का-अब भी भारतीय जनता पार्टी से तालमेल है, तो इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। इन धारणाओं का खंडन भी उन्हें ही करना है।

माया: आपके खिलाफ शराब और लाटरी-दो मामलों में जो फैसले हुए—उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका का राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है?

सिंह: शराब वाला मामला तो उच्चतम न्यायालय में जाकर सुलझा और मुझे न्याय मिला। मेरा विश्वास है कि लाटरी वाले मामले में भी मुझे न्याय ही मिलेगा। लेकिन एक बात आप मान कर चलिए कि न्यायपालिका की गरिमा गिरानेवालों को सभी खूब पहचान रहे हैं और उन्हें इतिहास क्षमा नहीं करेगा। शराब कांड में उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं, उनका मामले से कोई संबंध नहीं है।

माया: आपको जैसे और जिन स्थितियों में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, वह सिर्फ भोपाल का काम नहीं था। राजनीतिक लोग मानते हैं कि दिल्ली में भी आपके राजनीतिक शत्रु बहुत हैं?

सिंह: लोगों को मानने दीजिए। मैं पार्टी में एक ही आदमी को जानता और मानता हूं और वे हैं राजीव गांधी। बाकी सब आते हैं और चले जाते हैं। आते हैं, तो वे देवता हो जाते हैं और जाते हैं, तो कोई उनको पूछता तक नहीं। मैं शत्रुओं की गिनती इस आधार पर नहीं करता कि उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है। मेरा सारा जोर इस बात पर रहता है कि कौन लोग हैं जो पार्टी को हानि पहुंचा रहे हैं।

माया: ऐसे कुछ लोगों के नाम लीजिए।

सिंह: नाम तो आप लोग ही लेते रहते हैं। मैं क्यों लूं?

माया: अच्छा मैं कुछ नाम लेता हूं। आप बताइए कि वे सही हैं या नहीं?

सिंह: (चुप्पी)।

माया: गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित, कैप्टेन सतीश शर्मा...?

सिंह: यह आप हमारे बड़े नेताओं की सूची क्यों गिना रहे हैं?

माया: क्योंकि इन्हें आपका राजनीतिक शत्रु माना जाता है।

सिंह: आप मानते होंगे। मैं नहीं मानता।

माया: और अगर ये लोग खुद मानते हों कि आप उनके राजनीतिक शत्रु हैं, तो?

सिंह: उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो कोई ऐसा संकेत नहीं मिला।

माया: अब आप या तो नाटक कर रहे हैं या नाम लेने से डर रहे हैं? कांग्रेस कार्यसमिति में जब आपने कहा कि आप इस्तीफा 'दें' रहे हैं, तो आजाद ने प्रेस कांफ्रेंस में जा कर बोल दिया कि आपसे इस्तीफा 'मांगा' गया है।

सिंह: अब श्री आजाद पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेस मे तो उन्हें ही बात करनी है। मैं यह क्यों तय करूं कि वे क्या बात करेंगे? रही शीलाजी की बात, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके सहयोग और आत्मीयता के लिए मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर उन्हें धन्यवाद दिया है।

◆

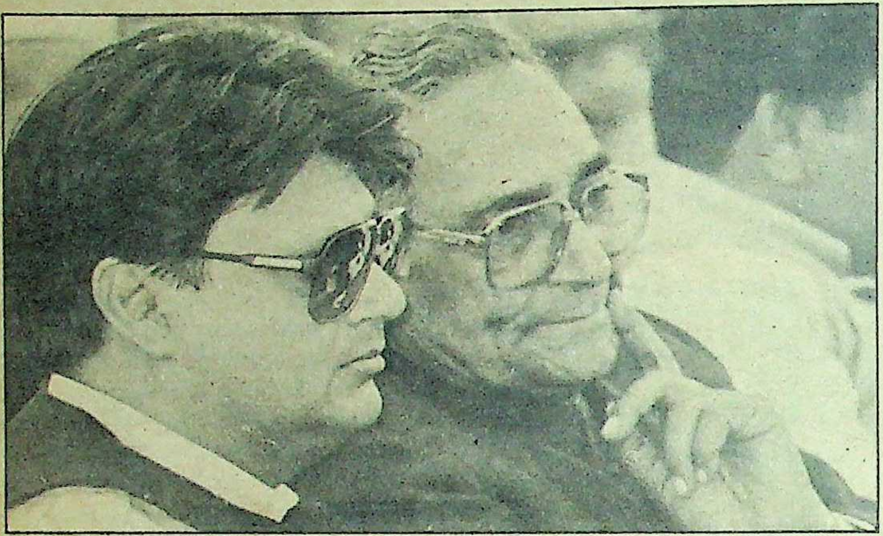

अर्जुन विरोधी जोड़ी: माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा

वोरा का शक्ति स्रोत

"मोतीलाल वोरा प्रधानमंत्री को इस नाते पसंद हैं, क्योंकि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है और मेहनत करने में उनका कोई सानी नही है"—राजीव गांधी के एक नजदीकी सांसद ने 'माया' से कुछ माह पहले कहा था। तब वोरा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री पद पर आसीन थे और करीब तीन साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। कांग्रेस-इ सांसद का उपर्युक्त कथन वोरा के व्यक्तित्व और समकालीन राजनीति में उनकी सफलता के रहस्य को काफी हद तक उद्घाटित करता है।

इसमें दो मत नहीं कि वोरा पहली बार मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पसंद से बने थे। किंतु उन्होंने अपनी नयी राह गद्दीनशीन होने के कुछ ही माह के भीतर चुन ली थी। सुरेश पचौरी और सुरेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में युवक कांग्रेस-इ का हरावल दस्ता, कृष्णपाल सिंह की अगुवाई में समाजवादी फोरम और टिकटवंचित नेताओं की जमात उनकी पूंजी बनी। लल्लू मुख्यमंत्री और खड़ाऊ सरकार के संबोधनों ने वोरा को मर्माहत किया और इनसे अर्जुन गुट को ही क्षति पहुंची। वोरा ने दिल्ली में जब अपनी जमीन और अपना कवच तलाशा, तो उनके समक्ष माधवराव सिंधिया का दामन थामने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। तब तक प्रकाश चंद सेठी का पराभव हो चुका था और अरुण नेहरू व विद्याचरण शुक्ल का इंका से निष्कासन। प्रारंभ से ही केंद्र से प्रदेश की राजनीति में आने के अनिच्छुक सिंधिया को वोरा के रूप में एक विश्वासपात्र नायक व साथी मिल गया। प्रदेश की राजनीति में कालांतर में दोनों एक दूसरे के पूरक एवं एक सिक्के के दो पहलू हो गये। ताजा नेतृत्व परिवर्तन में भी सिंधिया इस दृष्टि से दोहरे लाभ में रहे कि एक तो केंद्र में रहने की उनकी तमन्ना पूरी हुई, दूसरे मप्र में मुख्यमंत्री की कुरसी पर उनके शुभचिंतक व सहयोगी वोरा विराज गये।

संबंध कटु: अर्जुन सिंह और वोरा के सबंधों में खमीर तभी पड़ गया था, जब सिंह पंजाब के राज्यपाल थे। सिंधिया से हाथ मिलाने के बाद वोरा जब परदे पर आये, तो अकेले नही, वरन सिंधिया के साथ जोडी के रूप में। इसने वोरा को यकीनन अर्जुन गुट के लिए राजनीतिक बैरियों की पांत में खड़ा कर दिया। अर्जुन सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में भरसक जतन किया कि मोती-माधव की जुगल जोड़ी के दौरे रुक जायें। इसमें उनकी विफलता ने उजागर कर दिया कि आलाकमान अर्जुन सिंह पर तलवार लटकाये रखना चाहता है। युवक कांग्रेस के मोर्चे पर सिंह की बारंबार पराजय ने भी इसकी पुष्टि की कि उनको राह के रोड़ों से मुक्ति नहीं मिलेगी। रामेश्वर नीखरा को सेवादल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर राजीव गांधी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने इरादों का स्पष्ट संकेत दें दिया था। लेकिन बहुतेरे आत्ममुग्ध और मुगालतों के शिकार राजनेता इन संकेतों को बूझने में विफल रहे।

वोरा के मुख्यमंत्री बनने से नेतृत्व की वल्गा भी छत्तीसगढ़ (छग) के हाथों में पहुंच गयी है। छग को कभी शुक्ल बंधुओं की राजनीतिक जागीर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब यह अतीत की बात है। अर्जुन सिंह ने शुक्ल-बंधुओं की जड़ों में बीते बरसों में खूब मट्ठा डाला है। जहां तक वोरा व विद्याचरण के संबंधों का सवाल है, वोरा कभी भी महारथी या दिग्गज नेता नहीं रहे और वोरा और वीसी राजनीतिक लिहाज से कभी भी एक खेमे में नहीं रहे। वीसी ने पहली दफा वोरा के मुख्यमंत्री बनने का स्वागत अर्जुन सिंह से मुक्ति के स्वाभाविक उछाह में किया था। अलबेली गुटीय राजनीति दोनों को कुछ समय के लिए साथ ले आयी थी। अगर चंडीगढ़ जाने के बजाय अर्जुन सिंह लगातार मप्र के मुख्यमंत्री बने रहते, तो डा० कन्हैयालाल शर्मा, चित्रकांत जायसवाल, विट्ठलभाई पटेल, काकू भाई माय शालवार, रामचंद्र वाजपेयी, केएन प्रधान आदि अनेक नेताओं को एकबारगी कांग्रेस-इ छोड़ने प विचार करना पड सकता था, लेकिन कुरसी प वोरा के होने से ये तमाम विद्या-समर्थक कांग्रेस-इ के खूंटे से बंधे रहे।

वोरा का आत्मविश्वास: "छग में विद्याचरण कोई शक्ति नहीं हैं"—वोरा ने 'माया' से कहा—"और हम उनकी चुनौती का सामना करने में पूरी तौर पर सक्षम हैं।" वोरा मानते हैं कि छग परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ है और सरकार ने हरिजन आदिवासियों के हित की योजनाओं के क्रियान्वयन से वहां अपनी जड़े मजबूत की हैं। इससे इनकार करना गलत होग कि आलाकमान की नजरें आसन्न चुनावों पर और वोरा को दिल्ली से बाकायदा गुरु-मंत्र देकर भोपाल भेजा गया है। काबीने में हरिज आदिवासियों व पिछड़ों को ५० प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व देने के पीछे चुनावी चिड़ि की आंख भेदने की इच्छा काम कर रही है। वोरा का यह सघन प्रयास होगा कि शोषित सर्वहारा वर्ग के नेताओं को साथ लेकर चला जाये और इस वर्ग की सहानुभूति व विश्वास अर्जित किया जाये, जो पूर्व मुख्यमंत्री की ता और संबल रहा है। तेंदू पत्ता नीति में फेरबद न कर उसे यथावत जारी रखने के पीछे यही कारण है कि नीति बदलने या रद्द करने से

उनके दल के भीतर राजनीतिक बैरियों को वोरा के खिलाफ प्रचार करने और वंचितों, विशेषकर आदिवासियों में उनकी छवि बिगाडने का औजार मिल जाता।

बतौर मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा की स्थिति इस नाते सुविधाजनक है कि आकस्मिक राजनीतिक परिस्थितियों वश अर्जुन गुट सांप-छछूंदर की गति का शिकार हो गया है। अर्जुन गुट यदि निष्क्रिय रहता है, तो उसकी शक्ति व सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि वोरा के खिलाफ मुहीम छेड़ता है, तो इसे आलाकमान अस्थिरता उत्पन्न करने का षड्यंत्र मानेगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक महाभारत में यदा-कदा प्रेस की भी भूमिका रही है। पिछले मुख्यमंत्रित्वकाल में वोरा पर कुछ पत्रों को प्रश्रय व प्रोत्साहन देने के आरोप लगे थे। मगर अर्जुन गुट इस तरह के आरोपों को अब इस कारण नहीं उछाल सकेगा, क्योंकि अखबारों के जरिये राजनीति करने का खेल इस गुट ने भी कम नहीं खेला है। ताजा मिसाल दो स्थानों से प्रकाशित एक दैनिक की है, जिसे जबलपुर में सूचना प्रकाशन विभाग के सूचना केंद्र की इमारत अलाट कर दी गयी है और सूप्र विभाग को मन मसोसकर वहां से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री की यही इच्छा थी। राजधानी में डम-डम डिगा-डिगा मार्का अखबारों की फसल पनपाने का आरोप तो बरसों से अर्जुन सिंह पर है।

अर्जुन सिंह और वोरा के संबंधों में खमीर तभी पड़ गया था, जब सिंह पंजाब के राज्यपाल थे। सिंधिया से हाथ मिलाने के बाद वोरा जब परदे पर आये, तो अकेले नहीं, वरन सिंधिया के साथ जोड़ी के रूप में। इसने वोरा को यकीनन अर्जुन-गुट के लिए राजनीतिक बैरियों की पांत में खड़ा कर दिया।

प्रदेश की राजनीति में श्यामाचरण शुक्ल के इंका प्रवेश से भी किंचित गुणात्मक परिवर्तन आया है। यह सौ फीसदी सच है कि श्यामाचरण के इंका प्रवेश के लिए वही लाबी सक्रिय रही, जो वोरा को दुबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आज वोरा व श्यामाचरण एक ही मंच व खेमे में हैं। पारस्परिक मुलाकातों ने दोनों के रिश्तों को प्रगाढ़ किया है। श्यामाचरण के प्रदेश इंकाध्यक्ष बनने की संभावना अब इसलिए क्षीण है, क्योंकि दोनों (वोरा व श्याम) एक ही जाति व अंचल के हैं। वोरा के मुख्यमंत्री बनने से किसी राजपूत या आदिवासी के प्रदेश इंकाध्यक्ष बनने के आसार बढ़ गये हैं। संभावित जनों में फिलहाल दिलीपसिंह भूरिया, अरविंद नेताम, भंवर सिंह पोर्ते, गोविंद नारायण सिंह, कृष्णपाल सिंह के नाम लिये जा रहे हैं।

वोरा की रणनीति : जहां तक पार्टी के भीतर अर्जुन सिंह से लोहा लेने का सवाल है, कुछ प्रसंगों ने वोरा का हौसला बढ़ा दिया है। यह अकारण नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वोरा सबसे पहले सीधी-रींवा के दौरे पर गये, जबकि अर्जुन सिंह तिबारा मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले रायपुर-दुर्ग के दौरे पर गये थे। सिंधिया-वोरा ने विंध्य में अपनी जमीन बनाने की शुरुआत वस्तुतः गत वर्ष १४ मई को की थी, जब वे सतना व रींवा गये थे। तदुपरांत वे १४ दिसंबर को सीधी गये। वोरा का ३ फरवरी का ताजा दौरा इसी श्रृंखला की अटूट कड़ी है। वोरा की इस दौरान बड़ी सफलता यह रही कि विंध्य के इंका विधायकों—राजमणि पटेल, चंपा देवी, गरुड़ मिश्रा, इंद्रजीत पटेल, जगवा देवी, वृंदा सिंह और राम प्रताप सिंह ने यह लिखकर दे दिया कि वे मप्र में नेतृत्व परिवर्तन के राजीव गांधी के फैसले का स्वागत करते हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक, सिंधिया-वोरा के दौरों व हस्ताक्षर-अभियान में पूर्व संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा ने अहम भूमिका निभायी। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ विधायक डा० लालता प्रसाद खरे (अब आबकारी मंत्री) और गोपदबनास के कमलेश्वर द्विवेदी पहले से वोरा-सिंधिया के साथ हैं।

इस बात के आसार स्पष्ट हैं कि वोरा आगामी दिनों में अर्जुन सिंह के पांवों के नीचे से जमीन सरकाने और उनका कद घटाने का प्रयास करेंगे। अर्जुन सिंह के प्रबल विरोधियों—कैप्टेन जयपाल सिंह, कुमारी विमला वर्मा, चित्रकांत जायसवाल, रसूलअहमद सिद्दीकी, काकू भाई, डा० कन्हैयालाल शर्मा, विट्ठलभाई पटेल आदि को काबीना में जगह देकर अपने तेवर बता दिये हैं। केसीएस आचार्य की अध्यक्षता में उन्होंने निगमों की समीक्षा के लिए कमेटी भी बना दी है। उनका नजला कभी भी निगमाध्यक्षों पर गिर सकता है। अपनी क्षमता का कई बार परिचय दे चुके अर्जुन सिंह इस दफा जबर्दस्त चक्रव्यूह में फंस गये हैं। उन्हें अपने पुनरुत्थान के लिए सबसे पहले आलाकमान का विश्वास नये सिरे से अर्जित करना होगा। द्वापर में अपना अंगूठा एकलव्य को देना पड़ा था, मगर कलयुगी महाभारत में यकबयक ऐसा मोड़ आ गया है कि अर्जुन को अपना अंगूठा देना पड़ सकता है।

—सुधीर सक्सेना, भोपाल से

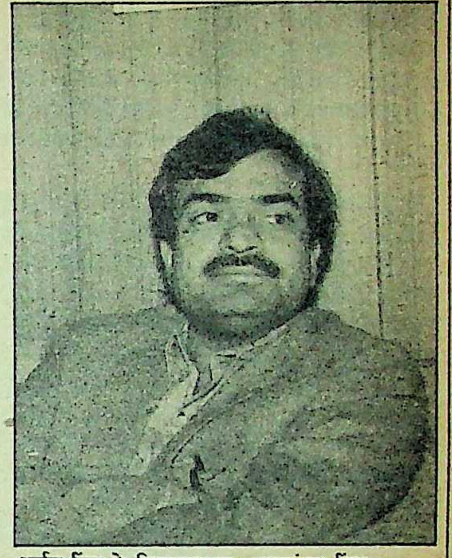

अर्जुन सिंह के सिपहसालार : रमाशंकर सिंह

यादव, सिंधिया के सबसे मुखर विरोधियों में से हैं और अगर अर्जुन सिंह इजाजत दे दें, तो सीधे मुकदमा दायर करने से लेकर शक्ति-प्रदर्शन तक करने में नहीं चूकेंगे।

वोरा पर सांघातिक जवाबी हमला : सिंह ने वोरा पर पहला और सबसे सांघातिक जवाबी हमला संघर्ष के इस दौर में किया—वह तेंदू पत्ता नीति को लेकर था। तेंदू पत्ता के सहकारी-सरकारीकरण करने और उसकी कमान अपने खास सांसद, भूतपूर्व कलक्टर अजीत जोगी के हाथ में सौंप देने से वोरा काफी नाराज थे और आते ही उन्होंने निर्णयों की समीक्षा का जो काम किया, उसमें शपथ लेने के २४ घंटे में घोषणा कर दी गयी कि तेंदू पत्ता नीति वापस ली जायेगी। ऐसा सुनहरा मौका सिंह चूकने वाले नहीं थे। उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी करके वोरा के इस कदम को स्वर्गीय श्रीमती गांधी और राजीव गांधी की इच्छा के खिलाफ बताया और वोरा के नाम सार्वजनिक पत्र लिखा, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा फैसला किया है, तो कृपया वापस ले लें। वरना इससे आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का बहुत नुकसान होगा।

अगले ही दिन वोरा को प्रेस से कहना पड़ा कि तेंदू पत्ता नीति बदलने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। वे केवल उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की नीति खोजना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने कार्रवाई की थी।

लेकिन वोरा पकड़े गये। दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक ने उन वायरलैस संदेशों की फोटो कापी छाप दी जो इस नीति को लगभग निरस्त करते हुए भेजे गये थे। बताया जाता है कि वोरा के इस विवादास्पद फैसले के पीछे 'झूठ बोले कौआ काटे' लिखने वाले, बीड़ी निर्माता राजनीतिज्ञ विट्ठलभाई पटेल थे। उन्होंने तेंदू पत्ता नीति की जबरदस्त खिलाफत की थी और बाकायदा पत्र लिख

कर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार उनके चुनाव क्षेत्र सागर में माफिया गिरोहों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के एक गिरोह के कहने पर स्थानीय पुलिस ने उन जैसे सम्माननीय नेता के खिलाफ कई मामले दर्ज कर लिये हैं।

एक और मामला : अजय (राहुल) सिंह के खिलाफ अकेला चुरहट का मामला नहीं है। एक लाइफ ट्यूबवेल कंपनी के वे महत्वपूर्ण कर्ताधर्ता हैं और उसे मध्य प्रदेश सरकार ने नौ करोड़ रुपए का भुगतान किया। झगड़ा इस बात पर है कि भुगतान किसके राज में हुआ—अर्जुन सिंह के या वोरा के? दोनों नेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे चुरहट लाटरी के साथ हुआ और वोरा को कहना पड़ा कि उन्होंने तो मंत्रिमंडलीय अनुमति की आशा में इस लाटरी को अधिकृत किया था। यह एक बोदा तर्क था, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्णय अगर मंत्रिमंडल अस्वीकार कर दे, तो इसका अर्थ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना होता है। स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल सिंह का सीधा हमला और आमना-सामना वोरा को सहना पड़ेगा और उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि कौन सा आदेश उन्होंने कब दिया था और क्यों दिया था? यह निश्चित है कि चुरहट कांड में अगर सिंह अभियुक्त बनेंगे, तो वोरा को सह-अभियुक्त के तौर पर अदालत में खड़ा होना पड़ेगा।

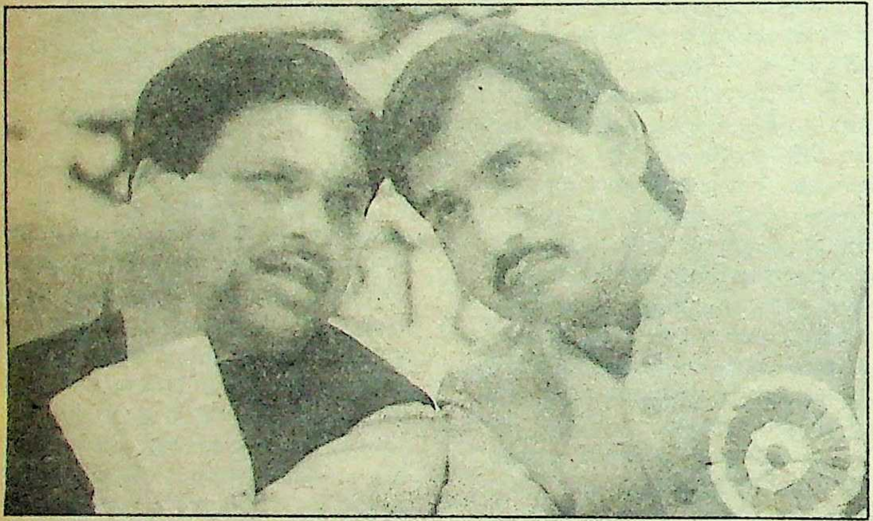

अर्जुन को मात देने पर विचार: सुरेश पचौरी और सुरेंद्र ठाकुर

सिंधिया की नाराजी : सिंधिया के पास अर्जुन सिंह से नाराज होने के अपने कारण हैं और वे एकदम निर्जीव हों, ऐसा भी नहीं है। सिंधिया को लग रहा कि उन्हें चंबल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना कर तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह ने उन्हें अपमानित किया है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा असंतुष्ट कहे जानेवाले, हवाई दौरों में से एक में झाबुआ जिले में 'महाराज' का हेलीकाप्टर न उतरने देने के लिए सरकार ने जिला प्रशासन को आदेश दिये, यह आरोप सिंधिया का है। इसके जवाब में अर्जुन सिंह कहते हैं कि उनके पास करने को और भी कई जरूर और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं। ऐसे ओछे कामों के लिए उनके पास वक्त नहीं है।

सिंधिया का अभियान इतना ही नहीं था। झाबुआ से आदिवासी विधायक श्रीमती जमुनादेवी उनके साथ प्रधानमंत्री निवास गयीं और वहां राजीव गांधी को अपना त्यागपत्र इस आरोप सहित सौंप दिया कि राज्य में आदिवासी विकास का काम नहीं हो रहा है। उनके आरोप के पीछे एक घटना का जिक्र किया गया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कुक्षी जिले में आदिवासी सम्मेलन बुलाने की इजाजत नहीं दी। श्रीमती जमुनादेवी का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री विधानसभा अध्यक्ष नहीं होते। लेकिन आदिवासियों और सूखा पीड़ितों की उपेक्षा का मुद्दा अर्जुन सिंह के खिलाफ केवल एक कोने से नहीं लगा। एक जमाने में एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक की हैसियत से सिंह के व्यक्तिगत मित्र और अब प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चंदूलाल चंद्राकर ने भी एकदम स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया। चंद्राकर की नाराजी की सिंधिया के क्रोध से, काफी सांगीतिक जुगलबंदी हो रही थी और इसीलिए जब सिंह के खिलाफ चुरहट का फैसला आया, चंद्राकर ने समाधि की सीमा तक पहुंच कर चुप्पी साध ली।

एक और चुप्पी बहुत रहस्यमय थी। सिंधिया के सबसे करीबी सांसद महेंद्र सिंह (जो सिंधिया द्वारा खाली की गयी गुना लोकसभा सीट से चुने गये हैं) चुरहट के फैसले के बाद शुरू हुई राजनीतिक गतिविधियों में बहुत निष्क्रिय रहे। सिंधिया के करीबी होने के बावजूद लोकसभा में चुरहट लाटरी पर हुई बहस में उन्होंने सिंह का काफी मुखर साथ दिया था। उन्होंने कहा था, "लाटरी का विरोध राजनीतिक शत्रुता को निकालने का एक सस्ता तरीका है। अगर कोई वीआईपी गरीब बच्चों के कल्याण के लिए काम करना चाहता है और उसके लिए ट्रस्ट भी बनाता है, तो विरोधी उसकी निंदा करने लगते हैं। कांग्रेस में जो भी आदमी ऊंची जगह पाता है, उसको बदनाम किया जाने लगता है। इसके बुरे नतीजे अगले चुनाव में पता लगेंगे।" (लोकसभा २२ अगस्त, १९८८ की बहस में से) यह सिंधिया के एक सबसे विश्वस्त सूबेदार की भाषा है।

लेकिन सिंधिया के सारे अनुयायी ऐसी भाषा नहीं बोलते। पिछले साल के आखिर में जब सिंह अपनी पत्नी के इलाज के लिए अमरीका गये थे, सिंधिया के खास दरबारी और ग्वालियर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश खंडेलवाल ने इस विदेश यात्रा को संदिग्ध बताते हुए इसकी जांच करवाने की मांग की। उन्हें और तीन अन्य पार्टी पदाधिकारियों को निलंबित करके सिंधिया के एक और खास नेता डाक्टर रघुनाथराव पापरीकर को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। पापरीकर ने कहा कि जाच की मांग का समर्थन तो वे भी कर हैं और इसीलिए उन्हें भी निलंबित किया जाना चाहिए। कांग्रेस के ताकतवर महासचिव गुलाम नबी आजाद ने सिंधिया और चंद्राकर की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की मांग करनेवालों को बहाल कर दिया। कमाल की बात यह है कि अर्जुन सिंह की अमरीका-यात्रा की जांच की मांग अब भी कायम है और पहले इसी मांग पर पदाधिकारियों को निलंबित कर देने वाले प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चंदूलाल चंद्राकर चुप हैं। अर्जुन सिंह खेमा अनुशासनहीनता के संरक्षण की इस राजनीति के खिलाफ हाईकमान से शिकायत करने जा रहा है।

इसमें कोई शक नहीं है कि अर्जुन सिंह को कुछ दिन तक अपनी रक्षा कमोबेश अकेले ही करनी पड़ेगी। कानूनी मोर्चे पर लड़ने में शायद उन्हें उतनी असुविधा न हो, जितनी राजनीतिक मोर्चे पर होगी। कारण सीधा है। उनके अपने योद्धा भी इस बात से नाराज और असंतुष्ट हैं कि उन्होंने इस बार के कार्यकाल में अपने पुत्र को ऊपर लाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की।

कांग्रेस के ही विधायक सत्यदेव कटारे का आरोप तो यहां तक है कि राहुल सिंह समानांतर सरकार चला रहे थे। उधर सिंह के ही खेमे के दुखी नेता कहते हैं कि सिंह पहले अपने पिता के जेल जाने को लेकर बदनामी सहते रहे और अब बेटे के कारण सांसत में हैं। अभी तो अर्जुन सिंह की हिटलिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन उनके पास उतने सैनिक नहीं हैं, जो हैं वे युद्ध के मूड में आयें—इसके लिए सिंह को अपनी शैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे। लेकिन जो हो, सिंह का पिछला रिकार्ड देखते हुए साफ है कि अपने विरोधियों को ठीक से निपटा देने की उनकी रणनीति का सामना इस बार दिल्ली से भोपाल तक बिखरे अनेक जाने-अनजाने नेताओं को करना होगा। इतना जरूर तय है कि यह लड़ाई आर-पार होगी। इस पार या उस पार!

—'माया' टीम

रेल पटरी समझौता

जब मंत्री अभियुक्त भी हो

सिन्धिया स्टेट रेलवे

गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं: दिल्ली रेल म्यूजियम में सिंधिया स्टेट रेलवे

सत्ताईस सितंबर, १९८५ को भारतीय रेलवे ने उस मामले में समझौता कर लिया जो उसने बारह साल पहले अपनी संपत्ति की चोरी और उसकी बिक्री के संदर्भ में दायर किया था। यह मामला माधवराव सिंधिया के खिलाफ दायर हुआ था। समझौता उस समय हुआ, जब सिंधिया केंद्र में रेल राज्यमंत्री के पद पर आसीन थे। सिंधिया के तहत काम कर रहे रेल मंत्रालय में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने 'अभियुक्त' माधवराव सिंधिया से सुलह हो जाने की अपील ग्वालियर के जिला न्यायाधीश के कार्यालय में की और तेरह साल से लटके इस मामले को एक घंटे में निपटा दिया गया।

मामला असल में १९२५ से आरंभ होता है। तब वर्तमान माधव राव सिंधिया के दादा हिजहाइनेस माधवराव सिंधिया (उनका भी नाम यही था) ने सिंधिया राज रेलवे की एक पटरी ग्वालियर रेलवे स्टेशन से जयविलास महल तक डाली थी, ताकि वीआईपी सीधे घर आकर रेल से उतर सकें। मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू और चाऊ-एन-लाई इस सुविधा का इस्तेमाल करनेवालों में रहे हैं।

इस पटरी का रखरखाव ग्वालियर स्टेट रेलवे का लाइट रेलवे विभाग करता था और इसे महाराजा सिंधिया की निजी संपत्ति माना जाता था। १९४८ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ग्वालियर रियासत का मध्य भारत राज्य में विलय हो गया और उस समय जो संपत्ति ग्वालियर राज्य ने भारत सरकार को सौंपी, उसकी सूची में इस पटरी का कहीं कोई जिक्र नहीं है।

१९५० में रेलवे की पुनर्संरचना हुई। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे (तब भारतीय रेल का यही नाम था) ने इस रेलवे को भी अधिग्रहण कर लिया। महल की रेल पटरियों का जिक्र तो तब भी नहीं हुआ, पर रेलवे ने १९५१ में जो नियम पुस्तिका निकाली, उसके पेज ३१३ पर कहा गया कि महाराजा सिंधिया इन पटरियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बुकिंग करानी होगी। इसके बाद से पटरियों के रखरखाव का खर्च राज परिवार की ओर से दिया जाने लगा। तत्कालीन गृह मंत्रालय ने महाराजा सिंधिया से सीधे पैसा वसूल करने के आदेश रेलदे को दिये थे। १९६१ में महल में बिछी पटरियों का मूल्यांकन रेलवे ने करवाया और तब उनकी कीमत चौहत्तर हजार तीन सौ चौदह रुपए आंकी गयी थी।

मामला तब से घुमाव लेता है। २९ सितंबर, १९७२ को माधवराव सिंधिया (वर्तमान रेल राज्य मंत्री) ने रेल पटरियां ग्वालियर के एक स्थानीय व्यापारी डाक्टर गोपाल कृष्णं छापरवाल को बेच दीं। डाक्टर छापरवाल ने ९९०० फुट पटरियां उखड़वा लीं—बाकी अब तक बची हैं। सिंधिया के व्यक्तिगत रिकार्ड में भारतीय रेलवे से तब किया गया उनका पत्र व्यवहार रखा है, जिसके अनुसार पटरियों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानते हुए बेचने की इजाजत दी गयी थी। डाक्टर छापरवाल ने शहर के दीनदयाल मार्केट के अपने गोदाम में ये पटरियां जमा करा लीं। ग्वालियर में रेलवे के एरिया सुपरिंटेंडेंट ने इसके खिलाफ स्थानीय झांसीरोड थाने में रिपोर्ट लिखायी और पुलिस ने गोदाम पर अपना गार्ड बिठा दिया। इसके बाद रेलवे ने सिंधिया के पक्ष में कई पत्र स्थानीय पुलिस

को लिखे, पर उनका कोई सकारात्मक या नकारात्मक नतीजा नहीं निकला।

लेकिन भारत सरकार के दूसरे महकमे भी तब अपना काम करते रहे थे। जैसे २७.८.१९२८ को ग्वालियर रियासत और तत्कालीन भारत सरकार के बीच हुए समझौते में कहा गया था कि चूंकि पटरियां रियासत की व्यक्तिगत भूमि पर बिछी हैं, इसलिए उनके इस्तेमाल का निजी अधिकार (तत्कालीन) महाराजा सिंधिया को होगा। पर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि ये पटरियां हिजहाइनेस की निजी संपत्ति हैं। यह तर्क इस आधार पर रखा गया था कि पटरियां ग्वालियर रियासत के खर्च पर बिछी थीं, महाराज के निजी खर्च पर नहीं। जिस जमीन पर ये बिछी थीं वह भी राज्य की संपत्ति थी, निजी पारिवारिक संपत्ति नहीं।

सिंधिया के व्यक्तिगत रिकार्ड में रेलवे के तत्कालीन सहायक इंजीनियर का स्वीकृति पत्र है, जिसमें पटरियां उखाड़ने की अनुमति दी गयी है। लेकिन १८ नवंबर, १९७६ को तत्कालीन मध्य रेलवे के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर एनएन शेट्टी ने ग्वालियर की अदालत में बयान देकर कहा कि यह अनुमति देने के अधिकार इतने छोटे अधिकारी के नहीं होते। शेट्टी ने यह भी कहा कि यह संपत्ति अगर है भी तो अकेले माधवराव सिंधिया की नहीं है। श्रीमती विजयाराजे सिंधिया और उनकी सारी संतानें इसमें भागीदार हैं।

अदालती फैसला: मामले का फैसला ग्वालियर के अतिरिक्त जिला जज की अदालत में हुआ और इसमें कहा गया कि रेल पटरियां किसी भी हाल में ग्वालियर के महाराजा और उनके परिवार की संपत्ति नहीं मानी जा सकतीं। इस फैसले में कहा गया कि कोर्ट फीस तक पर्याप्त नहीं दी गयी है और मुकदमे में असल में जो खर्च हुआ है, वह भारत सरकार को वापस मिलना चाहिए। यह फैसला हुआ और वे सारे विवाद 'अचानक समाप्त' हो गये जो इस मुकदमे का कारण बने। भारतीय रेलवे का यह सहसा हृदय परिवर्तन २७ सितंबर, १९८५ से हुआ और तब तक माधवराव सिंधिया विपक्ष से पक्ष में आकर केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बन चुके थे। तब इस समझौते से डाक्टर छापरवाल का नाम भी गायब हो चुका था। समझौता माधव राव सिंह और रेल-राज्यमंत्री के बीच हुआ। समझौता यह हुआ:

एक—चार हजार फुट रेलवे लाइन माधवराव सिंधिया की संपत्ति मानी जायेगी।

दो—जितनी पटरियां बेची जा चुकी हैं, उनकी कीमत 'केवल' इक्कीस हजार तीन सौ छत्तीस रुपए मानी जायेगी। (रेलवे ने यह रकम १० सितंबर, १९८५ को ही ले ली थी।)

तीन—थाना झांसीरोड में सिंधिया और छापरवाल के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द समझा जायेगा। रेलवे मध्य प्रदेश पुलिस को इस समझौते की जानकारी देगी, ताकि पुलिस अपना पहरा फौरन हटा ले।

समझौते पर रेलवे की ओर से मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और वरिष्ठ क्षेत्रीय महाप्रबंधक (झांसी) ने दस्तखत किये। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तत्कालीन कलक्टर शिवराज सिंह ने दस्तखत किये और एक चतुराई यह की कि लिख दिया कि आपराधिक मामले रद्द होने के अलावा बाकी सब मुद्दों पर सहमति है। बाकी मुद्दों से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है। माधवराव सिंधिया के समर्थक नरेंद्र सिंह (जो युवक कांग्रेस के स्वरोजगार सेल के राष्ट्रीय संयोजक हैं।) कलक्टर की इस टिप्पणी को एक अफसर की राजनीतिक 'सूझ' मानते हैं। नरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर 'महाराज' के खिलाफ एक भी सबूत होता, तो समय-समय पर आनेवाली सरकारें उन्हें क्यों छोड़तीं? बीच में तो जनता सरकार भी आयी और संविद सरकार भी रही।

राजनीतिक संरक्षण: यहीं आकर संपत्ति के इस मामले में राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगता है। ग्वालियर जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष भगवानसिंह यादव का आरोप है कि श्रीमती विजयाराजे सिंधिया, संविद और जनता, दोनों सरकारों में काफी प्रभावशाली थीं और अंततः यह उनकी पारिवारिक संपत्ति थी, इसलिए इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अब यह श्रीमती सिंधिया का दायित्व है कि इस आरोप को गलत साबित करें।

इस मामले में दिलचस्पिया और भी हैं। जैसे दोनों ओर से बड़े-बड़े वकीलों को नियुक्त किया गया था, लेकिन सिंधिया की ओर से कुल खर्च ११७६ रुपए ५० पैसे और रेलवे की ओर से १०९९ रुपए ५० पैसे आंका गया। इसमें स्टैंप फीस भी शामिल है।

—'माया'—टीम

माधवराव सिंधिया

'मुझ पर आरोप नहीं लग सकता'

ऐसी चर्चा है कि अर्जुन सिंह के जवाबी हमले के लिए जो हथियार सजाये जा रहे हैं, उनमें रेल पटरी कांड भी एक है। यद्यपि इस विवाद का समझौता कोई गुपचुप नहीं हुआ है और यह मामला आज से चार साल पहले का है, लेकिन इसे सत्ता के दुरुपयोग का रंग देकर अब उछालने के गुर तलाशे जा रहे हैं। जब माधवराव सिंधिया से उनके खिलाफ चल रही मुहिम के संबंध में बातें हुईं, तो वे हंसकर बोले, "मुझे मालूम है कि कुछ लोग हर तरह की अफवाह और बातें मेरे बारे में फैलाने पर तुले हैं। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह से दिल्ली एक-राजेंद्र नगर स्थित मकान में ढाई बजे दिन में मिला। एक पत्रकार को बताया गया कि खुफिया एजेंसियों ने गाड़ी नंबर तक नोट किये हैं। खैरियत है कि उस समय मैं तीन कांग्रेसी सांसदों और कुछ लोगों से भेंट कर रहा था। जब कुछ नहीं मिलता, तो ऊटपटांग बातें फैलायी जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री को मालूम है कि मैं उनका कितना आभारी हूं और मैं कभी भी कोई ऐसी बात नहीं सोच सकता जो उनको हानि पहुंचाये। फिर मुझे आवश्यकता भी क्या है? राजीवजी ऐसे व्यक्ति हैं, जिनसे विचारधारा और निजी स्तर पर मेरे संबंध सौभाग्यवश बहुत अच्छे हैं।"

रेल पटरी प्रकरण के बारे में सिंधिया कहते हैं, "जो आरोप मुझ पर लगाना चाहते हैं, वह लग नहीं सकता। मेरे पास हर तरह के दस्तावेज मौजूद हैं।" उनका कहना है कि १९०५ के करीब उनके दादा ने एक किसी की रेल लाइन अपने महल तक बिछवायी थी। इसका भुगतान चैक द्वारा किया गया था। इसका प्रबंध एफई दिशा ने किया था जो टाटा के साथ भी रह चुके थे, दिशा उस समय महाराज ग्वालियर के साथ कार्य कर रहे थे।

साठ के दशक में केंद्रीय रेलवे से अनुमति लेकर और यह तय करके कि यह रेल पटरी ग्वालियर की निजी संपत्ति है, उसको ७५,००० रुपए में एक प्राइवेट व्यक्ति को बेचा था। उसके ऊपर एक केस चला। यह सोचकर कि उसको कोई हानि न हो, सिंधिया ने इस बात की कोशिश की कि मामला तय हो जाये। यह केस श्यामाचरण शुक्ल के समय में चला था। बाद में यह कहा गया कि जब महाराजाओं की संपत्ति पर सरकार ने नियंत्रण कर लिया, तो पटरी पर भी सरकार का कब्जा माना जाना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व यह तय हुआ कि एक तिहाई हिस्सा सरकार का माना जाये। इसी बात पर फैसला हो गया। मजे कि बात यह है की करीब-करीब सारी पटरी, जो पुलिस के कब्जे में थी, गायब हो गयी। सिंधिया कहते हैं, "यह मामला उन तक रेल मंत्रालय में पहुंचने का सवाल नहीं था और केस से उनको कोई हानि नहीं हो सकती थी। मामला कानूनी और सही तरीके से सुलझाया गया। इसके सारे दस्तावेज मंत्रालयों में मौजूद हैं।" क्या कोई मानेगा कि ५०,००० से ७५,००० रुपए के लिए सिंधिया ने गड़बड़ की? ■

राजीव गांधी का कोई विकल्प नहीं

—भवानी सेनगुप्त

आज हम अपने वर्तमान राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। राजीव गांधी का राजनीतिक नेतृत्व चरमरा रहा है। लेकिन सत्तारूढ़ दल में ऐसा कोई नहीं है, जो उन्हें हटा सके और दल को एकजुट रख सके। दल में ऐसे नेता भी हैं, जो देश के सामने एक अजीबोगरीब नाटक कर रहे हैं—एक ओर वे राजीव गांधी के नेतृत्व के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजीव गांधी के प्रति अपनी वफादारी की कसमें खा रहे हैं, यही नहीं, विपक्षी दलों को केंद्र में सत्ता दिखायी दे रही है। जाहिर है, विपक्षी दलों का सपना तभी साकार हो सकेगा जब वे मतदाताओं के सामने योग्य विकल्प की स्पष्ट छवि रख सकेंगे। फिलहाल उनकी (विपक्ष) जो स्थिति है उसे देखकर तो यह नहीं सोचा जा सकता कि विपक्षी दल वर्ष के अंत तक ऐसा कर सकेंगे। न केवल इस खेमे में भारी फूट है, बल्कि अपने समृद्ध स्रोतों के बल पर कांग्रेस विभिन्न धड़ों को लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फिर सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे नेताओं की कोई कमी नहीं, जो विपक्षी नेताओं पर क्रूर आघात करने में सकुचाते नहीं।

अनुशासनहीनता: तमिलनाडु में कांग्रेस का सफाया और बिहार तथा मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल का संकट साथ-ही-साथ था। जनवरी के मध्य से ही बिहार में पार्टी भारी आंतरिक संघर्ष से गुजर रही थी। पांच केंद्रीय मंत्रियों को पटना की दौड़ लगानी पड़ी थी, ताकि अनुशासन पैदा किया जा सके। किंतु वे बेचारे भी असफल रहे और फिर नये राज्यपाल की नियुक्ति, नये प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति तथा नये मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो दौर आया वह सब कांग्रेस पार्टी के अंतर्विरोध, असंतोष तथा अनुशासनहीनता को ही उजागर करता है।

यह सारा कुछ किसी घटिया नाटक सा लगता है तथा यह संकेत देता है कि हमारी संसदीय राजनीति अपने बुरे दिनों की ओर बढ़ रही है। हालात जैसे हैं, उन्हें देखकर तो यही कहा जायेगा कि आगामी संसदीय चुनाव में ही नहीं, चुनाव की तैयारियों के दौरान भी स्थिति शांत नहीं रहेगी।

राजीव गांधी को अब इस बात का अफसोस होगा कि वे मूपनार और चिदंबरम द्वारा बनायी गयी 'रोमांचक योजना' के जाल में फंस गये। एक बार फिर राजीव गांधी ने सिद्ध कर दिया कि वे भारतीय राजनीति का गूढ़ रहस्य नहीं समझते। तमिलनाडु चुनाव का उनका अभियान राजनीतिक त्रुटियों की एक पूरी किताब है। उन्हें इसका आभास नहीं था कि वे भारत के एक ऐसे राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक है।

अब भविष्य अंधकारमय दीखता है—न केवल कांग्रेस-इ का, बल्कि लोकतंत्र का भी। लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री अपने उम्मीदवारों के चयन में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे। उन्हें स्थानीय गुटों के सामने झुकना होगा। स्थानीय गुट अपने विरोधियों से घिरे हुए हैं। संभावना यह है कि जिन्हें उम्मीदवारी मिलेगी, वे पार्टी में एक से ज्यादा विरोधी पैदा कर देंगे। ये विक्षुब्ध अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करेंगे। ऐसा लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में तो कांग्रेस-इ ही कांग्रेस-इ के खिलाफ लड़ेगी।

अगर विपक्ष एक सशक्त और योग्य विकल्प देने की बात मतदाताओं के मन में बिठा सके, तो कांग्रेस-इ चुनाव हार भी सकती है। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। अगर यह नहीं हुआ, तो कांग्रेस अगली सरकार का गठन थोड़े बहुमत से या फिर सबसे बड़े दल के रूप में या कई दलों के साथ मिलकर करेगी। यह लगभग तय है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और इसकी वजह यह होगी कि कोई भी उनके नेतृत्व को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगा। साहस और आत्मविश्वास ने तो कांग्रेसियों का बहुत पहले से ही साथ छोड़ दिया है। उनमें से बहुत थोड़े ही अपने बलबूते पर राजनीतिक समर्थन जुटा सकते हैं।

उन्हें इस बात का विश्वास तो नहीं होगा कि वे खुद के बूते पर चुनाव जीत सकते हैं या दल की बदौलत। ऐसी हालत में वे सत्ता पर पकड़ पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनायेंगे। अगले चुनाव प्रचार में हर तरह के दुष्कर्म होंगे। एक दूसरे पर दोषारोपण, चरित्रहनन तो मामूली बातें होंगी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बड़े-बड़े दंगे भी करा सकते हैं। हर तरह के ऐसे काम हो सकते हैं जिनसे लोकतंत्र को आघात पहुंचता है।

भोपाल और पटना में खेले गये नाटकों से कुछ खतरनाक बातें सामने आयीं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री और दल के अध्यक्ष अपने लोगों पर नियंत्रण खो बैठे हैं। दूसरा इतना ही महत्वपूर्ण तथा खतरनाक सच यह है कि दल के हर संघर्षरत गुट उनकी ही सौगंध ले रहे हैं। बिहार के ज्यादातर कांग्रेसी विधायक जो भागवत झा आजाद का पत्ता साफ करने में लगे थे, वे सभी राजीव गांधी के सच्चे अनुयायी होने का दावा भी कर रहे थे। ऐसा ही वे भी कर रहे थे, जिन्होंने आजाद को बचाने की कोशिशें कीं। भोपाल में भी ऐसा ही हुआ।

क्या इससे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मजबूत और सर्वव्यापी होगा? निश्चित रूप से नहीं। इससे सिर्फ दो और सच साबित होते हैं और दोनों ही बदरंग तथा भयावह हैं। राजीव गांधी एक ऐसा चिह्न बन गये हैं, जिन्हें सामने रखकर सभी गुट आपस में कट मरेंगे, क्योंकि वे असहाय हैं। अपनी चाहतों को पूरा करवाने में बिलकुल असमर्थ। उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्ता के दलालों ने अपने-अपने हिसाब चुकाने के लिए उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

विकल्प का अभाव: कांग्रेस में एक और निरंकुश सत्य है और वह यह कि राजीव गांधी का कोई विकल्प नहीं है। चिमनभाई मेहता का कहना सही था कि ज्यादातर कांग्रेसी विधायक और सांसद अपने नेतृत्व से अप्रसन्न हैं। लेकिन उनका यह सोचना कि यह अप्रसन्नता विद्रोह में बदल जायेगी, सरासर गलत है। कांग्रेस के सत्ता दलाल यह जानते हैं कि अगर उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं है, तो वे भी कुछ नहीं हैं। पार्टी में राजीव गांधी के अलावा ऐसा कोई नहीं है, जो दल को बांधकर रख सके। सच तो यह है कि राजीव को हटाते ही पार्टी के टुकड़े हो जायेंगे।

तमिलनाडु में कांग्रेस के सफाये से जो जख्म उभरा है, वह लोकसभा के चुनाव तक तो भरता नहीं नजर आता। अब चूंकि लोकसभा चुनाव के पूर्व किसी राज्य में चुनाव नहीं होना है, इसलिए राज्यों में विभिन्न गुटों में सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहेगा। हर गुट लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को नामांकित कराने के लिए जोर लगायेगा। हर महत्वपूर्ण गुट प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करेगा कि अगर उसके 'वैधानिक' दावे को नहीं माना गया, तो वह विपक्षी खेमे में चला जायेगा। सत्ता की यह लड़ाई हिंदी क्षेत्रों में ज्यादा घमासान होगी, जहां छह राज्यों में ही चालीस प्रतिशत सीटें हैं। बिहार में यह संघर्ष शुरू हो गया है। थोड़े दिनों में यह राजस्थान, मप्र और उत्तर प्रदेश पहुंच जायेगा। इनमें से कुछ राज्यों से संकेत तो मिलने लगे हैं। ■

हज़ारों मील के दुर्गम रास्तों पर मनों
भार के साथ आराम से चलते जाइए!

विक्रांत

एक भरोसेमंद टायर

जो उसी तकनोलॉजी से बना है जिसने
भारत के सर्वप्रथम ट्रक रेडियल टायर बनाए !

MAA COMMUNICATIONS VTL 488A HIN

भारी वर्षा, आकस्मिक बाढ़, मीलों तक जगह जगह गड्ढे ..... भारत की सड़कों पर ऐसी परिस्थितियाँ एक आम बात हैं । एक टायर विशेष रूप से ऐसी ही चुनौतियों का हज़ारों मील तक मनों भार के साथ सामना करने के लिए बनाया गया है । और वह है विक्रांत — एक भरोसेमन्द टायर जिसे बनाने वाली आधुनिक तकनोलॉजी का उपयोग भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

विश्व की सर्वोत्तम ' रेसिंग टायर तकनोलॉजी '

हर विक्रांत टायर को बनाने में ब्रिटेन की ' एवॉन ' कम्पनी की तकनीकी उत्तमता का हाथ है । रेसिंग टायरों में प्रथम स्थान प्राप्त ' एवॉन ' से ही वाहनों के सरताज —'रोल्स रॉएस'— अपनी अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं । विक्रांत का ' अनुसंधान और विकास ' विभाग इसी ' एवॉन ' तकनोलॉजी में आवश्यक सुधार कर इसे भारतीय सड़कों के अनुरूप ढालता है ।

वही तकनोलॉजी जिसने भारत के सर्वप्रथम ट्रक 'रेडियल' टायर बनाए

जब विक्रांत के 'अनुसंधान और विकास' विभाग ने अपना ध्यान ट्रकों के लिए 'रेडियल' टायर बनाने पर केन्द्रित किया तो उसका परिणाम था एक ऐसा शक्तिशाली टायर जिसने फ़ौरन अपना स्थान ब्रिटिश बाज़ार में बना लिया। और इस तरह विक्रांत ट्रकों के लिए 'रेडियल' टायर बनाने व उसे ब्रिटेन निर्यात् करने वाली भारत की सर्वप्रथम कम्पनी बनी।

विक्रांत — उच्च श्रेणी के वाहनों का मूल उपकरण

विक्रांत ने अपने काम द्वारा सम्पूर्ण परिवहन उद्योग में अपनी विश्वसनीयता को साबित कर दिया है । इसीलिए यह ' टैल्को ' और ' अशोक लेलैण्ड ' जैसी उच्च श्रेणी की कम्पनियों द्वारा निर्मित वाहनों के लिए मूल उपकरण के रूप में चुना जाता है । साथ ही यह अधिकतम राज्य परिवहन निगमों की बसों में रोज़ हज़ारों लोगों को देश भर में जगह जगह ले जाता है ।

अतः अगर आप आधुनिक तकनोलॉजी से बना एक ऐसा टायर चाहते हैं जो अपने को साबित कर चुका हो और जिसपर आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भरोसा कर सकें तो स्पष्ट है आप सिर्फ़ विक्रांत को ही चुनेंगे ।

VIKRANT

भरोसेमंद टायर
ज़िम्मेदार कम्पनी

आत्मनिर्भर होने की कोशिश : वोरा

मंत्रिमंडल का विस्तार

नये चेहरों को तरजीह

मोतीलाल वोरा ने
हाल में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके
क्या जताने की कोशिश की है?

८ मार्च को, राज्य विधान सभा के बजट सत्र के ऐन एक दिन पहले, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने एक तीर से कई शिकार कर डाले। एक तो उन्होंने इससे विधान सभा सत्र के पूर्व मंत्रिमंडल के विस्तार के अपने वचन को पूरा कर दिखाया, दूसरे टीम के सदस्यों के चुनाव में अपने तौर-तरीकों से यह दर्शा दिया कि विपरीत या इतर निष्ठा रखने वाले लोगों के लिए उनके काबीने में कोई ठौर नहीं है। इसके साथ ही मनोवांछित विस्तार कर उन्होंने फिर उजागर किया कि आलाकमान का वरदहस्त उन पर है।

मंत्रिमंडल का यह विस्तार, जिसे वोरा ने 'मिनी' विस्तार की संज्ञा दी, कुछ कारणों से टीम के प्रारंभिक गठन से अधिक मायने रखता है। विरोधी गुट और अनेक राजनीतिक पंडितों का यह कयास था कि मुख्यमंत्री वोरा सत्ता की रस्साकशी के 'हैंग ओवर' और झोंक से उबरकर इस विस्तार में गुटीय संतुलन को प्राथमिकता देंगे। यही कारण है कि पराजय से मर्माहत अर्जुन-गुट को आशा थी कि इस बार उसके शिविर के दो चार लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा।इसी धुंधली उम्मीद के साये में बंशीलाल धृतलहरे, भारत सिंह और महेश जोशी के नाम संभावित मंत्रियों के तौर पर राजनीतिक वातावरण में तैर रहे थे।

निराशा : उक्त परिप्रेक्ष्य में देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि इस विस्तार से अर्जुन-गुट और उसके नेताओं को निराशा हुई। यह अनुभूति इसलिए अधिक तीखी थी कि अर्जुन गुट के लगभग तीस विधायक गत ७,८ मार्च को दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और उन्होंने आलाकमान के द्वार भी खटखटाये थे। दिल्ली में इस असंतुष्ट लॉबी के नेताओं की—दो शीर्षस्थ नेताओं—श्रीमती शीला दीक्षित और माखनलाल फोतेदार से मुलाकात भी हुई थी।

विस्तार में समेटे गये विधायकों पर दृष्टिपात करें, तो साफ नजर आता है कि नये चेहरों को तरजीह दी गयी है। नौ में से छह-कमलेश्वर द्विवेदी, नंदलाल माटा, सत्यदेव कटारे, उदयभानु कुशवाहा, प्रियदर्शन धर्माधिकारी और किशनलाल कुर्रे पहली बार मंत्री बने हैं। संसदीय सचिव—राज्यवर्धन सिंह और बिदा प्रसाद भी नये चेहरे हैं। राजनांदगाव के सांसद शिवेंद्र बहादुर सिंह की पहल पर पहली बार अर्जुन सिंह के विगत मुख्यमंत्रित्वकाल में अल्पकाल के लिए मंत्री बने धनेश पाटिला भी नये चेहरों में गिने जा सकते हैं।

ग्वालियर चंबल का वर्चस्व : यह पहला मौका है कि राज्यमंत्रिमंडल में केंद्रीय रेलराज्यमंत्री माधवराव सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर-चंबल संभाग के पांच विधायकों को मंत्रियों की टीम में शामिल किया गया है। काबीना मंत्रियों-बालेंदु शुक्ल और शिवप्रताप सिंह के अलावा भैया साहब लोधी (पिछोर), सत्यदेव कटारे (अटेर) और उदयभानु कुशवाहा (भिंड) मध्य भारत के हैं। वस्तुतः वोरा ने इस विस्तार में गुटीय संतुलन के बजाय क्षेत्रीय संतुलन पर अधिक ध्यान दिया है। इंदौर से नंदलाल माटा, राजनांदगांव से धनेश पाटिला, जबलपुर से प्रियदर्शन धर्माधिकारी, बिलासपुर से—किशनलाल कुर्रे और रायपुर से—विजय गुरु का चयन इसी प्रवृत्ति का द्योतक है।

क्षेत्रीय और गुटीय संतुलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय-कमलेश्वर द्विवेदी एवं विजय गुरु को क्रमशः राज्यमंत्री बनाया जाना है। विंध्य के नेताओं में कमलेश्वर अर्जुन-गुट से निष्ठा की डोर तोड़ने वाले विधायकों में अग्रणी थे और उन्होंने सिंधिया-वोरा के—विंध्य के दौरे में खुलकर भाग लिया था (देखिए 'माया' १५ फरवरी '८९ का अंक)। कमलेश्वर के राजस्व एवं लोक स्वास्थ्य मंत्री बनने से—रामकिशोर शुक्ल का मंत्री बनना अधर में लटक गया है—और बिदा प्रसाद को संसदीय सचिव बनाने से—विंध्य का प्रतिनिधित्व भी पूरा हो गया है। बिदा को दरअसल इसलिए उपकृत किया गया है, क्योंकि वे उन विधायकों में सर्वप्रथम थे, जिन्होंने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि उन्हें नेतृत्व-परिवर्तन के दौर में ठाकुर हरबंस सिंह के बंगले पर धोखे से ले जाकर बलात रोका गया था।

मध्य प्रदेश की राजनीति में युवक कांग्रेस की लगभग डेढ़ दशक से उल्लेखनीय भूमिका रही है और इसने सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व से निर्देश ग्रहण कर प्रायः मुख्यमंत्री का साथ दिया है। इस समय भी युवक कांग्रेस का कैडर वोरा के साथ है और युवक कांग्रेस से जुड़े सत्यदेव कटारे समेत कुछ लोग उपकृत भी हुए हैं। नरसिंहगढ़ राजघराने के राज्यवर्धन सिंह का संसदीय सचिव बनना राजनीतिक दृष्टि से इसलिए अहमियत रखता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से पूर्व प्रदेश इंकाध्यक्ष सांसद दिग्विजय सिंह से विलोम भूमिका निभायी है। नरसिंहगढ़ और राघोगढ के राजनीतिक ध्वजवाहकों की निष्ठा में प्रारंभ से अंतर रहा और राज्यवर्धन ने सिंधिया की पुत्री के विवाह के प्रसंग पर उन लोगों को आड़े हाथों लिया था, जो शाही शादी की खिलाफत का झंडा उठाये हुए थे।

इनाम : बंशीलाल धृतलहरे और चरणदास महंत की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल में सतनामियों का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया था। सतनामियों के धर्मगुरु विजय गुरु को टीम में शामिल कर एक तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति की गयी है। स्व० मिनीमाता के पुत्र विजय गुरु को अर्जुन सिंह ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर मंत्री बनाया था और वह सिंह के प्रति कुछ समय पहले तक निष्ठावान भी थे। हाल में निष्ठा बदलने का इनाम उन्हें अब इस रूप में मिला है।

मंत्रिमंडल विस्तार से स्पष्ट है कि अपने ढुलमुलपन के लिए बार-बार कोसे गये वोरा के तेवर बदले हुए हैं। कहा जा सकता है कि वोरा अपनी पूर्वनिर्मित छवि को स्वयं तोड़ने के इच्छुक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम कौशिक की इच्छा के विपरीत जनता दल के अध्यक्ष विद्याचरण शुक्ल ने दुर्ग उपचुनाव में वोरा को जनता दल की ओर से 'वाक ओवर' दे कर खुद को घाटा और वोरा को नफा पहुंचाने का काम किया। वोरा के फैसलों और कामों से लगता है कि उन्होंने अपनी जड़ें फैलाने के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वियों की जड़ों में मट्ठा डालने का खेल भी सीख लिया है।

—सुधीर सक्सेना

हिटलर की वापसी

विजय पाटनी

'हिटलर'—जी हां, यह बोलचाल का घरेलू नाम है, छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक विजय कुमार पाटनी का, जिन्हें मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने हाल में मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम का चेयरमैन बनाया है। पाटनी के पुनर्वास की संभावना राजनीतिक वातावरण में तब से लहक रही थी, जब मार्च '८५ में मोतीलाल वोरा पहले-पहल मुख्यमंत्री बने थे। इसे पाटनी का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि उनकी नियुक्ति किसी-न-किसी कारण करीब चार सालों तक अटकी रही। पाटनी सन '७७ में जनता लहर में पहली बार विधायक चुने गये थे और सन् '८० में उनकी विजय की पुनरावृत्ति हुई। बिजली मंत्री के तौर पर वे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बिगड़े ढर्रे को काफी हद तक पटरी पर ले आये थे और अब वोरा ने उन्हें सर्वप्रमुख, लेकिन खस्ताहाल व अनियमितताओं की गुंजलक में कैद निगम सौंपा है। वस्तुतः इस कांटों के ताज के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके पास इस भारीभरकम बेढब निगम को दुरुस्त करने की योग्यता व हुनर हो। इस लिहाज से पाटनी की काबिलीयत अब कसौटी पर होगी। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि हाल के नेतृत्व-परिवर्तन के दौर में पाटनी नेपथ्य में सक्रिय रहे और उनके निजी बंगले पर भी बैठकों का दौर चला। यह और भी कम लोगों को मालूम होगा कि पाटनी के जीवन में 'पांच' के अंक का विशेष महत्व है, जैसे ५ मार्च को उनका विवाह हुआ, ५ मार्च को उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था और अंततोगत्वा ५ मार्च को ही वोरा ने उनकी नियुक्ति की फाइल पर हस्ताक्षर किये। पाटनी दंपति की दोगुनी खुशी का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि ५ मार्च को जिस दिन उन्हें यह शुभ-संवाद मिला, वह उनके विवाह का सिल्वर जुबिली डे-रजत जयंती दिवस था। बहरहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि हिटलर के आने से निगम के ढर्रे पर क्या असर पड़ता है और वे इस लस्टमपस्टम निगम को सुधारने के लिए कौन सी युक्ति काम में लाते हैं?

पंजप्यारे और चहेते

ललित कुमार जोशी

अर्जुन सिंह जब मुख्यमत्री थे, तो कई बरस पहले 'माया' ने कुंवर साहब के नवरत्नों का उल्लेख किया था। इन नव-रत्नों के सुनहरे दिन अब बीते कल की बातें हैं। दूसरे, अब दौर इन रत्नों का नहीं, पंजप्यारों और चहेतों का है। गृहमंत्री कैप्टेन जयपाल सिंह, खाद्य मंत्री कालेंदु शुक्ल, पंचायत, ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण मंत्री शिव प्रताप सिंह, मप्र दुग्ध महासंघ के चेयरमैन सांसद महेंद्र सिंह और मप्र राज्य परिवहन निगम के नये नवेले चेयरमैन विजय पाटनी को सिंधिया के पंजप्यारों की संज्ञा दी जा सकती है। दो और चेयरमैनों-विलास लाड और मनोहर बैरागी तथा कुछेक नजदीकी सांसदों को समेट लें, तो कहा जा सकता है कि सिंधिया— एकादश इन दिनों राजनीतिक परिदृश्य पर छायी हुई है। हालांकि, सत्ता की बागडोर वोरा-सिंधिया की मिलीजुली टीम के हाथों में है और सिंधिया के पंजप्यारे वोरा के भी खास हैं, किंतु वोरा की अंतरंग सलाहकार मंडली में कुछ और लोग भी शामिल हैं। ये हैं चित्रकांत जायसवाल, डॉ० कन्हैयालाल शर्मा, कु० विमला वर्मा, दुर्गादास सूर्यवंशी, रसूल अहमद सिद्दीकी और विट्ठल पटेल। वोरा के पुनर्सत्तारोहण से वोरा के चहेते अफसरों की भी वापसी हुई है। एम नटराजन फिर से पुलिस महानिदेशक हो गये हैं और सौम्य-शालीन ललितकुमार जोशी जन-संपर्क आयुक्त। सुखदेव प्रसाद दुबे और इकबाल अहमद अपर सचिव, एनबी लोहानी सचिव, मिथुन सिंह संयुक्त सचिव, बीएम अग्रवाल और केके तिवारी निज सहायक मुख्यमंत्री सचिवालय में लौट आये हैं। योग्य और युवा केडी कुकरैती फरवरी '८८ में वोरा के साथ दिल्ली चले गये थे। वोरा के निज सचिव की हैसियत से उनकी भी दिल्ली से भोपाल वापसी हुई है। लगता है कि वोरा को पहाड़ों के लोग कुछ ज्यादा ही भाते हैं। या फिर इसे संयोग कहा जायेगा कि एलके जोशी, केडी कुकरैती और एनबी लोहानी पहाड़ों यानी पर्वतीय अंचल के हैं।

पचौरी उवाच

यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच हुए समझौते का गैसपीड़ितों से संबद्ध संगठनों ने खुलकर विरोध किया, किंतु अधिकांश कांग्रेसी सांसदों व मंत्रियों ने अपने होंठ सी लिये। सितारा राजनेताओं की छोड़िए, कमेंट का मौका आया, तो गैस राहत मंत्री रसूल अहमद सिद्धीकी ने भी कन्नी काट ली। ऐसे माहौल में साहस एवं साफगोई का परिचय दिया, राज्यसभा के सदस्य एवं मप्र युवक कांग्रेस-इ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने। 'माया' की पचौरी से लंबी चर्चा हुई और वे बेलाग हो खुलकर बोले। पचौरी समझौते को इस नाते सामयिक मानते हैं कि गैसपीड़ितों को तुरंत मदद और मुआवजे की जरूरत थी। पंद्रह बीस साल बाद मदद मिलने का कोई औचित्य न था। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा—"मुआवजे की राशि पर्याप्त नहीं है। मुआवजा इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। भोपाल के नागरिकों की जान की कीमत इस राशि से नहीं आंकी जा सकती।" पचौरी का कहना है कि केंद्र सरकार को किसी और मद से राशि उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर उपचार मिले और वे बेहतर जिंदगी बसर कर सकें। भोपाल के प्रति अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए पचौरी ने २३ फरवरी को संसद में भी मुआवजे का मामला उठाया और मांग की कि केंद्र क्षतिपूर्ति राशि में अब तक प्रदत्त ६१ करोड़ रुपए न काटे, मिक के दुष्प्रभावों पर आरआरआई में अनुसंधान जारी रहे, यूका की भांति स्वयंसेवी संस्थाओं पर से मुकदमे उठाये जायें। संयोग से ये चारों बातें मान ली गयीं। गैस पीड़ितों के भले के लिए पचौरी की एक और योजना भी है। उनकी युक्ति है कि मुआवजे की आधी रकम नकद बांट दी जाये और आधी रकम बैंकों में जमा कर दी जाये। इस डिपाजिट से प्रतिमाह तीन करोड़ रुपयों की आय होगी जिससे ३० हजार व्यक्तियों को प्रतिमाह एक-एक हजार रुपए मिल सकेंगे। इसी भांति यूका की करीब ८७ एकड़ भूमि में सहायक उद्योग-इकाइयां खोल देनी चाहिए। साफगो सांसद पचौरी के प्रस्ताव चोखे हैं, परंतु सवाल यह है कि उन्हीं की पार्टी की सरकार उन पर अमल करेगी या नहीं और इसकी क्या गारंटी कि नौकरशाही अड़ंगे नहीं लगायेगी?

सुरेश पचौरी

—सुधीर सक्सेना

एक 'बागी' विधायक

धमाकेबाज विधायक रघु यादव ने कानफेड घोटाले का भंडाफोड़ कर हरियाणा में जो तूफान मचा दिया, वह क्या देवीलाल के पुत्रों के सत्ता-संघर्ष का ही एक अध्याय था?

रघु यादव

हरियाणा के राजनीतिक महाभारत में तीरंदाजी का अंदाज कुछ ऐसा है कि प्रत्यंचा किसी के हाथ होती है और तीर चलाने वाला कोई दूसरा होता है। इसका ताजातरीन उदाहरण विधायक रघु यादव का विस्फोटक कानफेड (हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव) घोटाला कांड है।

विद्रोह और विस्फोट के लिए प्रसिद्ध रघु यादव ने इस बार सहकारिता विभाग और सहकारिता राज्यमंत्री डा० रघुबीर सिंह कादियान को ऐसा जबरदस्त निशाना बनाया कि दल के नेता चौधरी देवीलाल को उन पर दलविरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी करके निलंबित करना पड़ा था। हालांकि बाद में तीव्र और व्यापक प्रतिक्रिया की बौछार सहन न कर सकने की स्थिति में उन्हें निलंबन आदेश वापस लेना पड़ा। निलंबन आदेश वापस लेते समय देवीलाल ने यह कहकर अपने आदेश की सार्थकता मनवायी कि उन्होंने रघु यादव का निलंबन सिर्फ पार्टी के अनुशासन की महत्ता को उजागर करने के लिए किया था।

घोटाला: असल में हुआ यह था कि रघु यादव ने सहकारिता मंत्रायल में हुई लगभग ८३० नियुक्तियों में की गयी अनियमितता का पर्दाफाश किया था। यादव का आरोप था कि उक्त नियुक्तियों के लिए न तो रोजगार कार्यालय से नाम मंगाये गये थे और न ही नियुक्तियां विज्ञापित की गयी थीं। यही नहीं, उन्होंने यह भी राजफाश किया कि तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों के लिए न तो विधिवत अनुमति ली गयी और न ही योग्यता अथवा आयु ही तय की गयी। मात्र सिफारिश को ही सबसे बड़ी योग्यता मानकर मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गयीं। रघु यादव ने आरोप को स्पष्ट करते हुए बताया कि सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की गयी लगभग ८३० नियुक्तियों में १९७ लोग सहकारिता मंत्री कादियान की सिफारिश पर लिए गये। १५६ लोगों पर मंत्री के 'गाडफादर' बताये जा रहे मुख्यमंत्री देवीलाल के सपूत रंजीत सिंह की कृपा रही। यही नहीं, देवीलाल के नाम पर ३५ लोगों की नियुक्ति की गयी और ७ लोगों की नियुक्तियां मुख्यमंत्री के कोटे के तहत हुई।

रघु यादव के अनुसार भर्तियों में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर भारी अनुकंपा रही। रंजीत सिंह के निर्वाचन क्षेत्र सिरसा के २१० आदमी, कादियान के क्षेत्र रोहतक के १८१ आदमी, मुख्यमंत्री के ओएसडी डा० केवी सिंह और बिजली मंत्री वीरेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र हिसार से ६१ लोग ही लिए गये। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व तो नाम का रहा। नियुक्ति में एक भी अपंग अथवा विधवा को स्थान नहीं मिला।

जाहिर है, इस तरह के आरोपों को कोई कैसे सहन कर सकता है? नतीजतन आवेश में आकर पार्टी अनुशासन की महत्ता उजागर करने का बहाना लेकर देवीलाल ने रघु यादव को निलंबित कर दिया था। जब इस संबंध में रघु यादव से पूछा गया, तो वे बोले, "मैंने तो भंडाफोड़ देवीलाल के नारे को ही ध्यान में रख कर किया। उन्हीं का तो नारा है, 'बिजली पानी का प्रबंध, भ्रष्टाचार बंद।' फिर वे इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं? सहकारिता विभाग, विशेषकर कानफेड पर मैंने भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाये हैं, वे बिलकुल सही हैं। यदि मुख्यमंत्री चाहें, तो उसकी उच्चस्तरीय जांच करा लें। अगर मैं गलत पाया जाऊं, तो मुझे सजा दी जाये, वरना दोषियों को दंडित किया जाये।"

रघु यादव के अनुसार, "तत्कालीन कानफेड प्रबंध निदेशक लैहम्बर सिंह (फिलहाल निलंबित) चलता-फिरता सचिवालय था, जो अपनी जेब में खाली, किंतु हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र लिए फिरता था।"

कानफेड के भ्रष्टाचार यहीं तक सीमित नहीं। ५५ रुपए के कंबल को १८५ रुपए में खरीदकर ११० रुपए में बेचने के विफल प्रयास की भी चर्चा है। फलतः लेवी चीनी की हर बोरी के साथ ७० रुपए में यही कंबल जबरन ग्राहकों पर लादा जा रहा है। यादव के अनुसार तरुण ब्रांड जो साबुन बाजार में २.१२ रुपए में बिकता है, उसे कानफेड २.६५ रुपए में बेच रहा है। उनका यह भी आरोप रहा कि कादियान ने अपने भतीजे बीएस कादियान—जो खरीद-फरोख्त के क-ख-ग से भी नावाकिफ हैं—को शिक्षा विभाग से डेपुटेशन पर बुलाकर कानफेड के कुरुक्षेत्र इलाके में जनरल मैनेजर पद पर कदाचित अधिकाधिक लाभ हथियाने के लिए लगा दिया।

देवीलाल का संकट: कादियान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और शरारतपूर्ण बताया। उनका कहना है कि रघु यादव ने एक विशेष प्रयोजन को लेकर और किसी अन्य व्यक्ति की कठपुतली बनकर उन पर कुत्सित आरोप लगाये हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब यादव ने इन आरोपों का दूसरे दिन विधानसभा में उत्तर देना चाहा था, तो अध्यक्ष ने न केवल अनुमति देने से इनकार किया था, बल्कि यादव के जबरन बोलने पर उन्हें सदन से बाहर करवा दिया था।

यद्यपि यह लड़ाई सीध-सीधे रघु यादव और डा० रघुबीर सिंह कादियान के बीच छिड़ी थी, किंतु जानकार सूत्र इसे मुख्यमंत्री के दो बेटों चौटाला और रंजीत सिंह में छिड़े सत्ता संघर्ष की नयी कड़ी मानते हैं। उल्लेखनीय है कि रघु यादव चौटाला के नजदीकी माने जाते हैं, तो कादियान रंजीत के। कहा जाता है कि रघु यादव का इस्तेमाल करके कादियान का भंडाफोड करना कुछ महीने पूर्व की पुलिस भरतियों को लेकर चौटाला और उनके करीबी गृह मंत्री संपत सिंह को सांसत में डालने और अपमानित करने का जवाबी हमला था।

कुछ भी हो, जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनते ही चौटाला ने जिस तरह का भंडाफोड़ करवाया है, वह इस बात का द्योतक तो है ही कि जहां ऐसा करके उन्होंने अपने वर्चस्व का डंका बजाया है, वहीं अपने भावी तेवर और रवैये की आगाही भी दे दी है। रघु यादव द्वारा उठाये गये समस्त प्रकरण में सर्वाधिक छीछालेदर मुख्यमंत्री देवीलाल की हुई। भ्रष्टाचार उन्मूलन का डंका पीटनेवाले के घर ही आरोपों की भरमार की शरमिंदगी के अतिरिक्त उन्हें रघु यादव के निलंबन को लेकर अलोकतांत्रिक होने का आरोप भी सहन करना पड़ा। क्योंकि जनता दल (अजीत गुट) के नेताओं रामनरेश यादव, सत्यप्रकाश मालवीय, रशीद मसूद आदि ने जब रघु यादव के निलंबन को राष्ट्रीय स्तर पर उछालकर उनकी स्थिति विषम बनायी तभी देवीलाल को अपना फैसला बदलना पड़ा।

बहरहाल, देवीलाल के पुत्रों चौटाला और रंजीत में जो युद्ध छिड़ा है, वह अभी भी रुका नहीं है। यद्यपि रघु यादव की वापसी ने सुलह-सफाई और माहौल शांत करने के रास्ते खोले हैं, किंतु आशंका तो यह है कि रंजीत जवाबी हमले-का तैयारी जरूर कर रहे होंगे। यदि जवाब-दर-जवाब का सिलसिला यों ही जारी रहा, तो देवीलाल की क्या स्थिति होगी? जो देवीलाल विपक्षी एकता के लिए इस कदर चिंतित हैं, वे अपने बेटों को ही एकमत नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन हमलों की परिणतिस्वरूप देवीलाल का भ्रष्टाचार विरोधी तेवर फीका पड़ जाने का खतरा भी बना हुआ है। जाहिर है, यदि विपक्षी नेताओं की कलई यों ही गृहयुद्ध के चलते खुलती रही, तो आगामी चुनाव में विपक्ष की क्या स्थिति होगी, इसे आसानी से समझी जा सकती है।

—रंजना कक्कड़

हाथों में हाथ, पर परस्पर टांग खिंचायी : डा० जगन्नाथ मिश्र, सत्येंद्र नारायण सिंह और भागवत झा आजाद

सत्येंद्र नारायण सिंह

छोटे साहब को गद्दी कैसे मिली ?

बिहार में इंका आलाकमान कोई ऐसा कदम उठाना चाहता था, जिससे अन्य राज्यों के असंतुष्ट विधायकों को भी सबक मिल सके। अप्रत्याशित सामूहिक पदत्याग से बने तिलिस्मी माहौल से लगा था कि राजीव गांधी अब कुछ ऐसा करेंगे, जिससे असंतोष का स्थायी इलाज हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी की बागडोर जगन्नाथ मिश्र को और सरकार की नकेल सत्येंद्र नारायण सिंह को सौंपना पड़ा है, उससे नहीं लगता कि राजीव गांधी ने बीमारी को निर्मूल कर दिया है। इतनी लंबी खींचतान के बाद हुए इस परिवर्तन से किस तरह का परिदृश्य बना है ?

२१ जून, १९७७ को जब जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री पद की लड़ाई कर्पूरी ठाकुर से हार गये थे, तब उन्हें भी इस बात की कल्पना नहीं रही होगी कि इस पराजय के ठीक बारह वर्ष बाद ११ मार्च, १९८९ को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में उन्हें सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुन लिया जायेगा।

बिहार के प्रथम वित्तमंत्री स्व० अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार के राजनीतिक खाते में अब तक मानो पराजय-ही-पराजय दर्ज रही हो। स्वयं अनुग्रह नारायण सिंह मुख्यमंत्री पद के चुनाव में डा० श्रीकृष्ण सिंह से परास्त हुए थे और उनके पुत्र सत्येंद्र नारायण सिंह पर भी कभी सत्ता का अनुग्रह नहीं रहा। पर अब जबकि सत्येंद्र नारायण सिंह पर सत्ता देवी की कृपा हो गयी है, तो राजनीतिक विसंगतियों की कष्टप्रद स्थिति ने उन्हें घेर रखा है। एक तरफ बगावत का तूफान खड़ाकर

असली सत्ता मुट्ठी में : डा० जगन्नाथ मिश्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उनका स्वागत करते हुए इंकाई

भागवत झा आजाद की कुरसी उलटने में कामयाब विधायकों की फौज पूरी हेकड़ी के साथ आश्वस्त बैठी है कि उन लोगों की किसी भी जायज-नाजायज आकांक्षा को खारिज करने का दुस्साहस नये मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ आमलोग इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि क्या भागवत झा आजाद की भांति खम ठोंककर सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जमे माफियाओं की जड़ों से मिट्टी झाड़ने का जोखिम उठा सकेंगे या फिर किसी तरह बीच का रास्ता निकालकर सांसत से बचे रहने की कोई तरकीब निकालेंगे ? सच तो यह है कि आजाद ने जिस तरह अपने लड़ाकू तेवर से आम बिहारियों के बीच सत्ता के प्रति पहली बार आस्था जगाने की पेशकश की थी, उसे सत्येंद्र नारायण सिंह जारी रख पाते हैं या नहीं, इसी पर सबकी नजर गड़ी हुई है।

अंतर्द्वंद्व भरा नाटक: बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर चले लंबे ऊबाऊ नाटक के अंतिम अंक में एकबारगी सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम जोर पकड़ गया। दरअसल, इस नाटक के पहले अंक में दिल्ली दरबार में इस बात पर विशेष माथापच्ची हो ही नहीं रही थी कि आजाद की जगह किसे मुख्यमंत्री बनाया जाये, बल्कि सबके-सब इसी पहेली को सुलझाने में लगे थे कि आखिर डा० जगन्नाथ मिश्र को कहां और किस रूप में ठौर दी जाये जिससे दिल्ली दरबार की अकड़ भी ढीली न दिखायी दे और जगन्नाथ भी संतुष्ट होने को विवश हो जायें। वैसे शुरू में कुछ सलाहकारों की राय थी कि पुरानी बातों को बिसराकर जगन्नाथ मिश्र को ही बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाये। इन सलाहकारों का तर्क था कि आगामी चुनाव के संग्राम को बिहार में जगन्नाथ ही पार लगा सकते हैं। पर दूसरी तरफ कुछ सलाहकार इस तर्क पर अडिग थे कि जगन्नाथ को अगर सत्ता सौंप दी गयी, तो यह साबित हो जायेगा कि आलाकमान ने आखिरकार घुटने टेक दिये। बहरहाल, तमाम तर्क-वितर्क चल रहे थे कि ७ मार्च को पटना में बैठे जगन्नाथ को फौरन दिल्ली पहुंचने का फरमान मिला। लिहाजा, उसी दोपहर जगन्नाथ दिल्ली रवाना हो गये, हालांकि उन्होंने सबको बताया कि दिल्ली वे अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जा रहे हैं, उन्हें आलाकमान ने नहीं बुलाया है। इस बार के सत्ता-परिवर्तन के दौरान जगन्नाथ मिश्र अप्रत्याशित रूप से गंभीर थे और पहले की भांति न तो वे सुर्खियों में रहने के लिए बेवजह बयान दे रहे थे और न ही दिल्ली से मिलनेवाले संकेतों के बारे में अपने विश्वस्त समर्थकों को ही कुछ बता रहे थे। जगन्नाथ मिश्र इस बार आश्वस्त थे कि उन्हें कुछ मिलनेवाला है, इसलिए ऊपर से वे अपने को बिलकुल उदासीन बनाये हुए थे। पटना हवाई अड्डे पर ७ मार्च की दोपहर जब वे दिल्ली के लिए विदा हो रहे थे, तो प्रेस छायाकारों ने तस्वीर लेने के लिए उन्हें घेर रखा था। पर जगन्नाथ ने फीकी हसी के साथ सबको निरुत्साहित करते हुए कहा, "आप लोग बेवजह अपनी रील बर्बाद न करें। मेरा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा।"

७ मार्च को ही आजाद-राज में सिंचाई मंत्री रहे लहटन चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया था। बहरहाल, ७ मार्च की शाम दिल्ली पहुंचने पर जब जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री निवास को सूचना दी कि वे पहुंच चुके हैं, तो फौरन उन्हें बुला लिया गया। लिहाजा, उसी शाम राजीव गांधी से उनकी देर तक बातचीत हुई। पूरी बातचीत के बाद भी जगन्नाथ मिश्र को यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उन्हें कौन-सी जिम्मेदारी मिलनेवाली है। अलबत्ता, बातचीत सुखद हुई थी, इसलिए जगन्नाथ काफी आशान्वित थे। अगले ही दिन ८ मार्च की शाम कांग्रेस महामंत्री और बिहार के प्रभारी एआर मल्लू ने यह घोषणा की कि जगन्नाथ मिश्र तारिक अनवर की जगह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाये गये हैं। जिस समय यह घोषणा हो रही थी, उस समय भागवत झा आजाद गया में अपनी पदयात्रा संपन्न कर वहीं रुके हुए थे। जगन्नाथ मिश्र के नाम की घोषणा के साथ आजाद-समर्थकों की रही-सही उम्मीद भी समाप्त हो गयी। आजाद ने अपने समर्थकों से हंसकर कहा भी, "आप लोगों को धीरे-धीरे शाक सहन करने के लिए तैयार किया जा रहा है। बस अब बड़ा धमाका झेलने के लिए दो-

एक-दिन दिल थामे रहिए।"

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिये बैठे तारिक अनवर अपने वास्ते मुख्यमंत्री पद के लिए लाबिंग करते हुए आश्वस्त थे कि अगर इस मुहिम में वे कामयाब नहीं भी हुए और कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो भी गया, तो भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार ही रखा जायेगा। पर जगन्नाथ मिश्र की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद तारिक दूसरी संभावना पर विचार करने लगे कि या तो अल्पसंख्यक के नाम पर मुख्यमंत्री पद की दौड में उनकी बाजी लह जायेगी या फिर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुला लिया जायेगा।

जगन्नाथ मिश्र के मनोनयन की घोषणा के बाद फिर दो दिन तक कोई फैसला नहीं हुआ। इस्तीफा दिये बैठे सभी बिहारी धुरंधर अपने भविष्य के बारे में जानने को बेचैन थे, पर किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था।

केंद्रीय मंत्री बिंदेश्वरी दुबे को तो पहले से ही ताकीद कर दी गयी थी कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वे हिलने की हिमाकत भी न करें, पर केंद्रीय राज्यमंत्री ललितश्वेर प्रसाद शाही भी मायूस होकर शिथिल पड गये थे। पहले ही राजपूत व ब्राह्मण लाबी ने उनकी उम्मीदवारी को ध्वस्त कर दिया था। अब दो ही फार्मूलों पर विचार हो रहा था कि मुख्यमंत्री पद पर किसी राजपूत को बिठाना श्रेयस्कर होगा या किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को। पिछड़ी लाबी के अव्वल उम्मीदवार बिहार सरकार के स्थायी काबीना मत्री लहटन चौधरी का ठस व्यक्तित्व राजीव गांधी को कत्तई प्रभावित नहीं कर सका। सीताराम केसरी ने भी अपनी उम्मीदवारी मे कम जोर नहीं लगाया था। पर उनके नाम पर हलके ढंग से भी सोचने की जरूरत नहीं समझी गयी। बलिराम भगत की योग्यता से क्योंकि राजीव पहले से वाकिफ थे, इसलिए उनके नाम पर भी कभी विचार नहीं किया गया। इस तरह बात एक ही बिंदु पर आकर ठहर गयी कि किसी राजपूत को ही मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाये। अगर माधवराव सिंधिया को मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ कराने में राजीव कामयाब हो गये होते, तो बिहार में किसी पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो जाती। पर किसी भी कांग्रेसशासित प्रांत में राजपूत मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं था, इसलिए भी यह विवशता थी कि किसी राजपूत को मुख्यमंत्री बनाया जाये। राजपूत फार्मूले पर दिल्ली दरबार को अंतिम रूप से केंद्रित देखकर अल्पसंख्यक लाबी ने भी इस तर्क के साथ जेहाद छेड़ा कि किसी कांग्रेसशासित प्रांत में क्योंकि मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए बिहार में किसी मुस्लिम को ही मुख्यमत्री बनाया जाये। मुस्लिम उम्मीदवारों में जहां पहले से तारिक अनवर सक्रिय थे, वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर तथा वर्तमान केंद्रीय राज्यमंत्री रफीक आलम के नाम भी जोर-शोर से सामने आये। पर आलाकमान अंतिम रूप से फैसला कर चुका था, इसलिए अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री का नारा भी बेअसर साबित हुआ। मुख्यमंत्री पद हेतु राजपूत उम्मीदवारों में सिर्फ दो नाम थे—असम के राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह तथा सत्येंद्र नारायण सिंह। भीष्म नारायण सिंह के नाम पर भारी विरोध था और यह कहा जा रहा था कि न तो प्रदेश की राजनीति से उनका कभी लगाव रहा है और न ही एक कुशल प्रशासक की ही योग्यता उनमें है। उनकी बस एक ही योग्यता है कि वे हर परिस्थिति में नेहरू परिवार से प्रतिबद्ध रहे हैं। भीष्म-विरोधियों का तर्क था कि इस समर्पण का पेंशन राज्यपाल के रूप में तो अरसे से वे पा ही रहे हैं। सीताराम केसरी जैसे लोग भीष्म की तुलना में सत्येंद्र नारायण सिंह को कबूलने के लिए तैयार थे।

अतीत: १९६९ में कांग्रेस से गये सत्येंद्र नारायण सिंह को पंद्रह वर्षों बाद ६ अक्तूबर, १९८४ को जनतापार्टी से कांग्रेस में लाने के पीछे राजीव गांधी की भी भूमिका रही थी। १९८४ के मार्च महीने में हुए राज्यसभा के चुनाव में जब जनतापार्टी के प्रत्याशी शहाबुद्दीन चुनाव हार गये, तो शहाबुद्दीन की हार का सारा दारोमदार सत्येंद्र नारायण सिंह के माथे मढ़कर जनतापार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सत्येंद्र नारायण सिंह को बिहार जनतापार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। सत्येंद्र नारायण सिंह चंद्रशेखर के इस दुर्व्यवहार से उस समय काफी आहत थे और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं कांग्रेस में रहा, मुझे इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ा। सत्येंद्र नारायण सिंह के इस कथन के बाद से ही उन्हें कांग्रेस में लाये जाने का प्रयास शुरू हो गया था। विपक्ष में रहने के बावजूद सत्येंद्र नारायण सिंह का संबंध श्रीमती गांधी से सदैव मधुर ही रहा और यही वजह थी कि कर्पूरी ठाकुर से अपनी हार के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने श्रीमती गांधी की मदद ली। २१ जून, १९७७ को जनतापार्टी विधायक दल में मुख्यमंत्री पद के चुनाव के दौरान कर्पूरी ठाकुर से हारने का घाव सत्येंद्र नारायण सिंह भूले नहीं थे। लिहाजा, १९ अप्रैल, १९७९ को जनता विधायक दल की बैठक में कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ वातावरण खड़ा कर कर्पूरी को मुख्यमंत्री पद से हटवाने में सत्येंद्र नारायण सिंह कारगर हो गये थे और इस बार 'किंगमेकर' की भूमिका निभाते हुए उन्होंने रामसुंदर दास को जनता सरकार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। पर कर्पूरी ठाकुर भी चुप नहीं बैठे थे। कुछ ही दिनों बाद कर्पूरी ठाकुर जब रामसुंदर सरकार के विरुद्ध अपने पक्ष में बहुमत जुटाकर अविश्वास प्रस्ताव लाये, तो सत्येंद्र नारायण सिंह ने तत्काल श्रीमती गांधी से बात की और रामसुंदर सरकार को सदन में कांग्रेस का समर्थन दिलवा दिया था जिससे कर्पूरी ठाकुर को फिर हाथ मलकर रह जाना पड़ा था। जनतापार्टी टूटने के बाद कर्पूरी ठाकुर लोकदल में शामिल हो गये थे और सत्येंद्र नारायण सिंह चंद्रशेखर के साथ जनतापार्टी में ही

क्या जातिगत व्यूह से निकल पायेंगे ? : मुख्यमंत्री बनने पर अपने समर्थकों के साथ सत्येंद्र नारायण सिंह

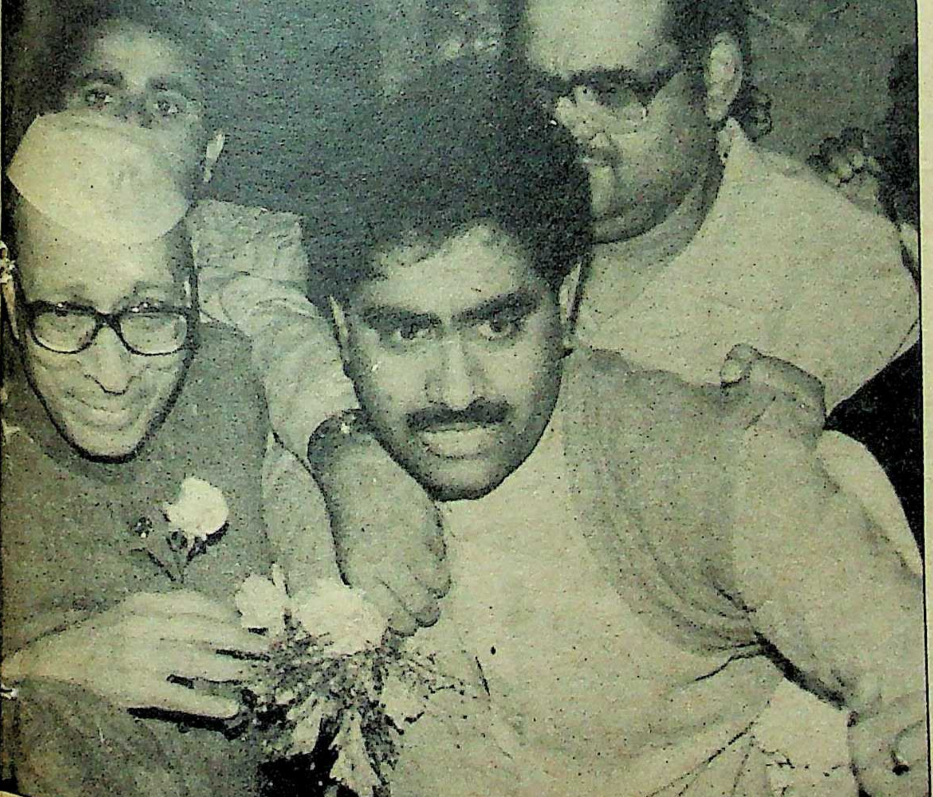

साक्षात्कार/ सत्येंद्र नारायण सिंह

प्रदेश के हित में जो भी बेहतर होगा, करूंगा

१९५२ से १९५७ तक कांग्रेस के सांसद और फिर १९६२ में पंडित विनोदानंद झा के मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री रह चुके सत्येंद्र नारायण सिह ने १९६९ में कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के दरम्यान नीलम संजीव रेड्डी के सवाल पर श्रीमती गांधी का रुख उन्हें रास नही आया। हालांकि कांग्रेस छोड़ने के पहले जब श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल उठा था, तो सिंह श्रीमती गांधी के कट्टर समर्थक थे। अत्यंत भावुक और संवेदनशील होने के कारण ही सत्येंद्र नारायण सिह ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी कूटनीति को महत्व नही दिया। स्वस्थ राजनीतिक मूल्यों के प्रति उन्होंने सदैव आग्रह रखा और शायद इसलिए लंबी अवधि तक क्षमतावान होने के बावजूद उनकी राजनीति को ग्रहण लगा रहा। अपने सोच में सत्येंद्र नारायण सिह कितने जनवादी हैं, इसका पता उनके इसी कथन से चलता है जब जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश करने के बीच की अवधि में उन्होंने कहा था कि मैं अगर आज की तारीख में अपनी उम्र से ४० वर्ष छोटा होता, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया होता। पर अब इस उम्र में मैं वैसा काम नहीं कर सकता हूं। प्रस्तुत हैं, 'माया' से उनकी बातचीत के अंश :

माया : *अपने कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए आप कैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता देंगे?*

सिंह : *मैं लंबी-चौड़ी बातों में कभी यकीन नहीं रखता हूं। बिहार के विकास के लिए मेरे मन में क्या सपने हैं, यह मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। जन आकांक्षाओं को अगर मैं निष्ठापूर्वक पूरा कर सका, तो मैं अपने को भाग्यवान समझूंगा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस प्रदेश की तरक्की हर कीमत पर चाहते हैं। मैं उसे पूरा करने के लिए कृतसंकल्प हूं।*

माया : *तारिक अनवर ने आपके मंत्रिमंडल में शपथ लेने से क्यों इनकार कर दिया?*

बिहार के विकास के लिए मेरे मन में क्या सपने हैं, यह मैं नहीं मेरा काम बोलेगा। जन आकांक्षाओं को अगर मैं निष्ठापूर्वक पूरा कर सका, तो मैं अपने को भाग्यवान समझूंगा।

सिंह : *ऐसा किसी विवाद या मतभेद के कारण नहीं हुआ। वे शपथ लेंगे।*

माया : *अब्दुल गफूर ने मुख्यमंत्री के रूप में आपके चयन को लेकर कई उलटी-सीधी टिप्पणी की है?*

सिंह : *क्या मैं भी उलटी-सीधी टिप्पणी करूं? हर टिप्पणी का जवाब दिया ही जाये, यह जरूरी नहीं। मैं सबके प्रति सम्मान और सद्भाव लेकर सदैव चला हूं, आज भी चल रहा हूं और आगे भी चलता रहूंगा।*

माया : *मध्य बिहार में हिंसा के कठोर वातावरण को समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे?*

सिंह : *हिंसक गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं, मैं पहले उनसे बात करना चाहूंगा। मेरी कोशिश होगी कि वे सब इस समाज के आदर्श नागरिक बनें। हरिजन बस्ती में जाकर काम करूंगा। इस समस्या को पूरी सवेदना से निबटाना होगा।*

माया : *झारखंड आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है?*

सिंह : *छोटानागपुर व संथालपरगना की समस्या पर हमने उस क्षेत्र के विधायकों की बैठक की। विचार-विमर्श कर रहा हूं, रास्ता निकलेगा ही। आदिवासी हमारे अंग हैं, उन्हें कैसे दुखी होने देंगे। आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, व हरिजनों के विकास के लिए हमारी सरकार सदैव तत्पर रहेगी।*

माया : *बिहार की शिक्षा मरणासन्न स्थिति में है। क्या आपके राज में कुछ सुधार आयेगा?*

सिंह : *मैं आया हूं, तो सुधार आयेगा ही।*

माया : *क्या आप भी मुख्य सचिव बदलेंगे?*

सिंह : *अफसरों के बीच कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए कि यह मेरा है, वह उसका है। ऐसा करने से ही अफसर उदासीन होते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि प्रदेश का हर अधिकारी अपनी पूरी क्षमता से पूरे सम्मान सहित काम करे। मुख्यसचिव के बदलने का सवाल कहां उठता है?*

माया : *सहकारिता के क्षेत्र में आपकी नीति क्या होगी? सहकारी माफिया के खिलाफ आपका रुख क्या होगा?*

सिंह : *प्रदेश के हित में जो भी बेहतर होगा, करूंगा। जितनी भी सख्ती अपनानी पड़े, अपनाऊंगा। हां, डा० जगन्नाथ मिश्र, बिंदेश्वरी दुबे, स्व० चंद्रशेखर सिंह तथा भागवत झा आजाद के समय में जितने भी अच्छे काम हुए, उसे जारी रखा जायेगा।*

माया : *ट्रांसफर-पोस्टिंग का धंधा क्या फिर शुरू होगा?*

सिंह : *वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण या पदस्थापन का फैसला मंत्रिमंडल से होगा, इसलिए किसी भी किस्म की अनियमितता या पक्षपात की गुंजाइश ही नहीं होगी।*

—वि०कु०झा

बगावत के तेवर: अब्दुल गफूर

नहीं चाहिए मंत्रीपद: तारिक अनवर

पिछड़ गये: लहटन चौधरी

टिके रह गये। फिर चरण सिंह से नाराज होकर कर्पूरी ठाकुर ने लोकदल-क का गठन किया और आखिरकार २७ जनवरी, १९८३ को लोकदल-क को जनतापार्टी में मिला दिया। सत्येंद्र नारायण सिंह ने जनतापार्टी में कर्पूरी ठाकुर के पुनरागमन का कड़ा विरोध किया था। आखिरकार फिर कर्पूरी ठाकुर के कारण ही उन्हें चंद्रशेखर से अपमानित होने की नौबत आयी। लिहाजा, उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौट जाने का फैसला लिया। कांग्रेस-प्रवेश के पूर्व श्रीमती गांधी और राजीव गांधी से भी सत्येंद्र नारायण सिंह मिलते रहे। उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह ने कहा भी था, "इस लड़के से मेरी लंबी बातचीत हुई और मैं काफी प्रभावित हुआ।" सत्येंद्र नारायण सिंह के कांग्रेस में आने के कुछ ही दिनों बाद दुर्भाग्यवश श्रीमती गांधी चल बसीं और कांग्रेस में राजीव-युग की बहाली हो गयी। उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह कांग्रेस में आ तो गये, लेकिन दुर्भाग्यवश हाशिये पर ही रहे। राजीव गांधी ने उन्हें कभी कोई पद तो नहीं दिया, पर इस बुजुर्ग नेता के प्रति सम्मान उनके मन में सदैव बना रहा।

भागवत झा आजाद को जब बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो वह सत्येंद्र नारायण सिंह ही थे, जिन्होंने आलाकमान से आजाद के लिए पुरज़ोर पैरवी की थी। सत्येंद्र नारायण सिंह को कांग्रेस में लाने में अपनी भूमिका के कारण राजीव गांधी सत्येंद्र के प्रति सहृदय थे और शायद यही वजह थी कि आजाद को हटाने की विवशता के बाद राजीव ने अपनी आयुधशाला में अरसे से संजोकर रखे इस अचूक आयुध को चुनाव वर्ष में आजमाना तय किया। वैसे ८ मार्च की शाम को ही सत्येंद्र नारायण सिंह को हलका आभास मिल गया था कि रेस में वे आगे हैं, क्योंकि उस शाम दिल्ली दरबार से उन्हें इशारा किया गया था कि वे बिहार की आगामी राजनीतिक संभावनाओं के बारे में नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र से विचार-विमर्श करें। उस शाम जगन्नाथ मिश्र से सत्येंद्र नारायण सिंह की देर तक बात भी हुई थी। लेकिन आलाकमान सत्येंद्र नारायण सिंह के नाम को 'लीक' होने से बचाये हुए था।

ऐसे बने मुख्यमंत्री: ११ मार्च को तीन बजे दिन में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में नये नेता के चुनाव की घोषणा की गयी। सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम १० मार्च तक पूरी तरह स्पष्ट हो गया था, फिर भी कुछ लोग भीष्म नारायण सिंह के नाम पर उम्मीद टिकाये बैठे थे। केंद्रीय राज्यमंत्री केके तिवारी ने पटना में एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को फोन किया कि सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम बिलकुल स्पष्ट हो गया है। पर एक-दो वैकल्पिक नाम भी तय किये गये हैं कि अगर मध्यप्रदेश की भांति विधायकों ने सत्येंद्र नारायण सिंह के नाम पर विद्रोह किया, तो फिर कोई एक वैकल्पिक नाम आगे कर दिया जायेगा। पर तिवारी ने उक्त वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को कहा कि वे वैकल्पिक नाम किसके हैं, यही पता नहीं चल रहा। बहरहाल, ११ मार्च को केंद्रीय पयवेक्षक भजनलाल, डा० राजेंद्र कुमारी वाजपेयी और कांग्रेस महासचिव एआर मल्लू पटना पहुंच गये। केंद्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से विदा ही हो रहे थे कि अचानक तारिक अनवर को निर्देश मिला कि वे भी पर्यवेक्षकों के साथ पटना चले जायें। पर सत्येंद्र नारायण सिंह को पर्यवेक्षकों के साथ नहीं, बल्कि पीछे से पहुंचने को कहा गया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बिहार के नेताओं में एकमात्र तारिक के आने को लेकर तारिक-समर्थक सुखद संभावनाओं की समीक्षा में डूबे थे। स्वयं तारिक अनवर भी काफी प्रफुल्लित थे। बहरहाल, तीन बजे निर्धारित समय पर सदाकत आश्रम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई और एकमत से सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार कर लिया गया। उसी समय तय किया गया कि नये मुख्यमंत्री आज ही शाम छह बजे शपथ ग्रहण कर लेंगे। तब यह स्पष्ट नहीं था कि सत्येंद्र नारायण सिंह का एकल शपथग्रहण होगा या मंत्रिमंडल के साथ। समय भी इतना कम था कि मंत्रियों के नाम तय करने में काफी आपाधापी मची। आखिरकार एक दर्जन काबीना मंत्रियों की फेहरिस्त बनकर तैयार हुई। सदाकत आश्रम में उस समय स्थिति बेहद संगीन हो गयी, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक भजनलाल ने तारिक अनवर को आलाकमान का आदेश सुनाया कि उन्हें सत्येंद्र नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में बतौर काबीना मंत्री आज ही शपथग्रहण करना है। यह आदेश तारिक के लिए अप्रत्याशित था। दिल्ली में ही अगर उन्हें यह बात बता दी गयी होती, तो पटना वे शायद आते भी नहीं। भजनलाल की हिदायत को तारिक ने साफ नकार दिया कि जब तक वे स्वयं आलाकमान से दिल्ली जाकर बात नहीं कर लेंगे, तब तक काबीना मंत्री के रूप में शपथग्रहण का कोई सवाल ही नहीं उठता। बुरी तरह विचलित तारिक को जगन्नाथ मिश्र ने भी समझाने की कोशिश की कि आलाकमान के आदेश की अवहेलना उन्हें नहीं करनी चाहिए। पर रुआंसे तारिक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हुए। शपथग्रहण समारोह में वे राजभवन तक गये और जब सबसे आखिर में शपथ के लिए उनको पुकारा गया, तो शपथ लेने के लिए तैयार नहीं हुए। मुख्यमंत्री पद गंवाकर भी शपथग्रहण समारोह के दौरान भागवत झा के चेहरे पर हरदम हंसी बनी रही। शपथग्रहण समारोह के बाद अपने लोगों से अंतरंग बातचीत में आजाद ने कहा भी, "राजभवन में उस नौजवान को देखकर मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। उसका चेहरा असहनीय रूप से मायूस था। पर मेरे खिलाफ बगावत का झंडा सबसे पहले उसी ने उठाया था, उसे क्या मिला? मेरी तो सिर्फ कुरसी

गयी, पर उसने तो अपना संपूर्ण राजनीतिक कैरियर गंवा दिया।"

तारिक की दिल्ली-दौड़: १२ मार्च को तारिक दिल्ली गये। इस बीच सत्येंद्र नारायण सिंह ने भी उन्हें संवाद भिजवाया कि वे अपना हठ छोड़ दें। पर तारिक ने कहा कि बिहार में २७ मुस्लिम विधायक हैं जिनमें कई लोग उनसे ज्यादा योग्य हैं, इसलिए उन्हीं लोगों में से किसी को उनकी जगह ले लिया जाये। वे तो सांसद रहकर ही प्रसन्न हैं। तारिक ने कहा कि आलाकमान उनके पुनर्वास के प्रति चिंतित है, इस बात के वे कायल हैं, पर वे राज्य काबीना में मंत्री पद नहीं कबूलेंगे। जाहिर है तारिक को पिछले दिनों की बगावत को भड़काने का दंड मिला था। तारिक अनवर ने जब भागवत झा आजाद के खिलाफ विक्षुब्ध गतिविधियां शुरू की थीं, तो उन्हें हिदायत दी गयी थी कि वे ऐसा न करें और मिलजुल कर काम करें। पर तारिक अपनी धुन में लगे रहे। तारिक अनवर को जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, तो यह बात किसी कांग्रेसी को नहीं पची थी। पर मजबूर होकर सबने आलाकमान के हुक्म को सिर आंखों पर लिया था। आजाद के खिलाफ डा० जगन्नाथ मिश्र जैसे तत्कालीन विक्षुब्धों ने तारिक को ही मोहरा बनाया। तारिक भी तब भ्रम में आ गये, जब जगन्नाथ मिश्र और रामाश्रय प्रसाद सिंह जैसे धुरंधर उनके दरबार में हाजिरी लगाने लगे। धीरे-धीरे तारिक पूरी तरह विक्षुब्धों की गिरफ्त में आ गये। तभी से आलाकमान की नजर तारिक पर टेढ़ी थी। तारिक क्योंकि बिना किसी जड़-मूल के, बेहद आसानी से सदैव राजनीतिक शिखर पर रहे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बना दिये गये थे, इसलिए उनकी अमर्यादित महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की गद्दी को हसरत से देखने लगी। यहीं तारिक पिटे। फिर मंत्रिमंडल में शपथ न लेकर उन्होंने दूसरी बड़ी गलती कर डाली। बहरहाल, तारिक तो बिदके ही, पर अब्दुल गफूर ने भी कम विषवमन नहीं किया। सत्येंद्र नारायण सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस की राजनीति अभी भी वीपी सिंह की दहशत से संचालित हो रही है। यही वजह है कि सत्येंद्र नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया।

एक अभद्र घटना: शपथग्रहण के दौरान घटी एक अभद्र घटना ने यादवों के पोप रामलखन सिंह यादव को इतना दग्ध कर दिया कि ऐन शपथग्रहण के बीच वे बगावत का झंडा लिये हुए राजभवन से निकल गये। शपथग्रहण के समय जब रामलखन सिंह यादव राजभवन पहुंचे, तो उन्हें यह कहकर शपथ लेनेवाले मंत्रियों की कुरसी पर बिठा दिया गया कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाना तय हुआ है। प्रसन्नचित्त रामलखन सिंह यादव शपथ लेनेवाले मंत्रियों के वास्ते लगी कुरसी पर जा बैठे और उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी मिल गयीं कि भजनलाल की उन पर नजर पड़ी। भजनलाल ने फौरन आवाज देकर उन्हें बुला लिया और कहा, "रामलखनजी तुम्हें तो शपथ नहीं लेनी है। तुम वहां क्यों बैठे हो?" इतना सुनते ही रामलखन सिंह यादव उत्तेजित हो उठे और सीधे राजभवन से निकल गये। रामलखन सिंह यादव के इस अपमान से यादवों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था। एक यादव नेता ने 'माया' से कहा, "देखता हूं चुनाव में यादवों का एक भी वोट कांग्रेस कैसे ले लेती है?" रामलखन सिंह यादव इतने अपमानित हुए कि अगले ही दिन उन्हें अस्पताल में भरती होना पड़ा। इस तरह बगावत की लपटें राजभवन से ही निकलनी शुरू हो गयीं। सत्येंद्र नारायण सिंह को इसे झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

हाथों-हाथ विरोध: रामलखन सिंह यादव

> **रामलखन सिंह यादव उत्तेजित हो उठे और सीधे राजभवन से निकल गये। रामलखन सिंह यादव के इस अपमान से यादवों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था। एक यादव नेता ने 'माया' से कहा, "देखता हूं चुनाव में यादवों का एक भी वोट कांग्रेस कैसे ले लेती है?"**

जगन्नाथ की मनमानी: सत्येंद्र नारायण सिंह और डा० जगन्नाथ मिश्र की टीम बिहार में उतारने के लिए कमलापति त्रिपाठी ने राजीव गांधी को बधाई दी और कहा कि ये दोनों नेता बिहार में चुनाव के समय कांग्रेस को कामयाबी दिलवायेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर बिहार के दिग्गज राजनीतिक पंडितों को इस बात पर संदेह है कि सत्येंद्र नारायण सिंह से जगन्नाथ मिश्र की ज्यादा दिन निभ पायेगी! मंत्रियों की सूची ही जब बन रही थी, तो जगन्नाथ मिश्र अपने लोगों के अधिकाधिक नाम जुड़वाने के लिए तत्पर हो गये। लिहाजा, राजभवन में ही क्षुब्ध होकर सत्येंद्र नारायण सिंह यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि तब सारा मंत्रिमंडल उन्हें ही बना लेने के लिए कहिए।

वैसे भी जगन्नाथ मिश्र के अध्यक्ष पद पर आगमन से बहुतेरे लोग आशंकित हैं जो इस बात से वाकिफ हैं कि जगन्नाथ मिश्र अपने जख्म का बदला अत्यंत निर्ममतापूर्वक लेने में माहिर हैं। यही वजह थी कि अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेश्वर मिश्र को हटा दिया और अपने 'बिहार जन विकास मंच' से संबद्ध दयानंद झा को जिले का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। जगन्नाथ विरोधियों का कहना है कि जगन्नाथ मिश्र अगर पूर्वग्रहग्रस्त होकर काम करते रहेंगे, तो संगठन का काम अत्यंत कठिन हो जायेगा। फिलहाल, सत्येंद्र नारायण सिंह पर कम और जगन्नाथ मिश्र पर लोगों की नजर ज्यादा गड़ी है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बगावत करके उन्होंने तीन-तीन मुख्यमंत्रियों की सत्ता उलट दी। लिहाजा, उन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के समर्थक उनसे खार खाये बैठे हैं। जगन्नाथ विरोधी जमात इस रणनीति में जुटी है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ही जगन्नाथ मिश्र को कदम-कदम पर परेशान किया जाये और संगठनसंबंधी उनके हर फैसले को दिल्ली जाकर चुनौती दी जाये। जगन्नाथ समर्थक यह भी प्रचार कर रहे हैं कि सत्येंद्र नारायण सिंह महज चुनाव तक के लिए मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के बाद तो जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा भी आलाकमान ने कर रखा है। इस तरह की चर्चाओं से जगन्नाथ विरोधी जमात अभी से परेशान है कि कैसे जगन्नाथ मिश्र को कांग्रेस दफ्तर में ही विवादास्पद बना दिया जाये, ताकि भविष्य की संभावनाओं पर ताला लग जाये। दूसरी बात, इस चर्चा से कि चुनाव के पश्चात सत्येंद्र नारायण सिंह की जगह जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री होंगे, निश्चित रूप से सत्येंद्र व जगन्नाथ के संबंधों में कटुता आयेगी। पर इसमें दोष जगन्नाथ मिश्र से ज्यादा उनके फूहड़ और जल्दबाज समर्थकों का होगा। जगन्नाथ मिश्र स्वयं मंजे हुए व्यवहारकुशल राजनीतिक हैं, जो कम से कम मुंह पर दुश्मन से भी पूरी मिठास के साथ पेश आते हैं। पर उनके सलाहकार व समर्थक सदैव उन्हें विवादास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं।

क्या भागवत झा आजाद बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे? आजाद समर्थकों का कहना है कि आजाद पूरे बिहार पदयात्रा का कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। बहरहाल, बेशुमार संभावनाओं और आशंकाओं के बीच फंसी बिहार राजनीति में आनेवाले दिनों में इतना जरूर है कि कई टूटे समीकरण फिर जुड़ेंगे और कई जुड़े समीकरण फिर बिखरेंगे।

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार/प्रभाकर

लोगों के
हो गये।
र सत्येंद्र
कि तब
कहिए।
पद पर
स बात से
का बदला
ही वजह
पहले ही
मेटी के
दया और
दयानंद
दिया।
ाथ मिश्र
हेंगे, तो
जायेगा।
म और
गड़ी है,
बगावत
ता उलट
समर्थक
ी जमात
रूप में ही
न किया
ी दिल्ली
यह भी
ह महज
बाद तो
ायदा भी
र्चाओं से
कि कैसे
वादास्पद
ाओं पर
के चुनाव
जगन्नाथ
सत्येंद्र व
समें दोष
जल्दबाज
मंजे हुए
कम मुंह
आते हैं।
व उन्हें
देते हैं।
हार की
र्थकों का
ात्रा का
बेशुमार
ी बिहार
र है कि
कई 'जुड़े

कुमार झा
मार/प्रभाकर

बेशर्म कहीं के!
कौन मैं?
लेकिन देख तो तुम रही हो
मेरे ब्रान्डो की तरफ!
ना ना मैं कुछ नहीं देख रही.
मुझे पता था, तुम और
लड़कियों की तरह नहीं.

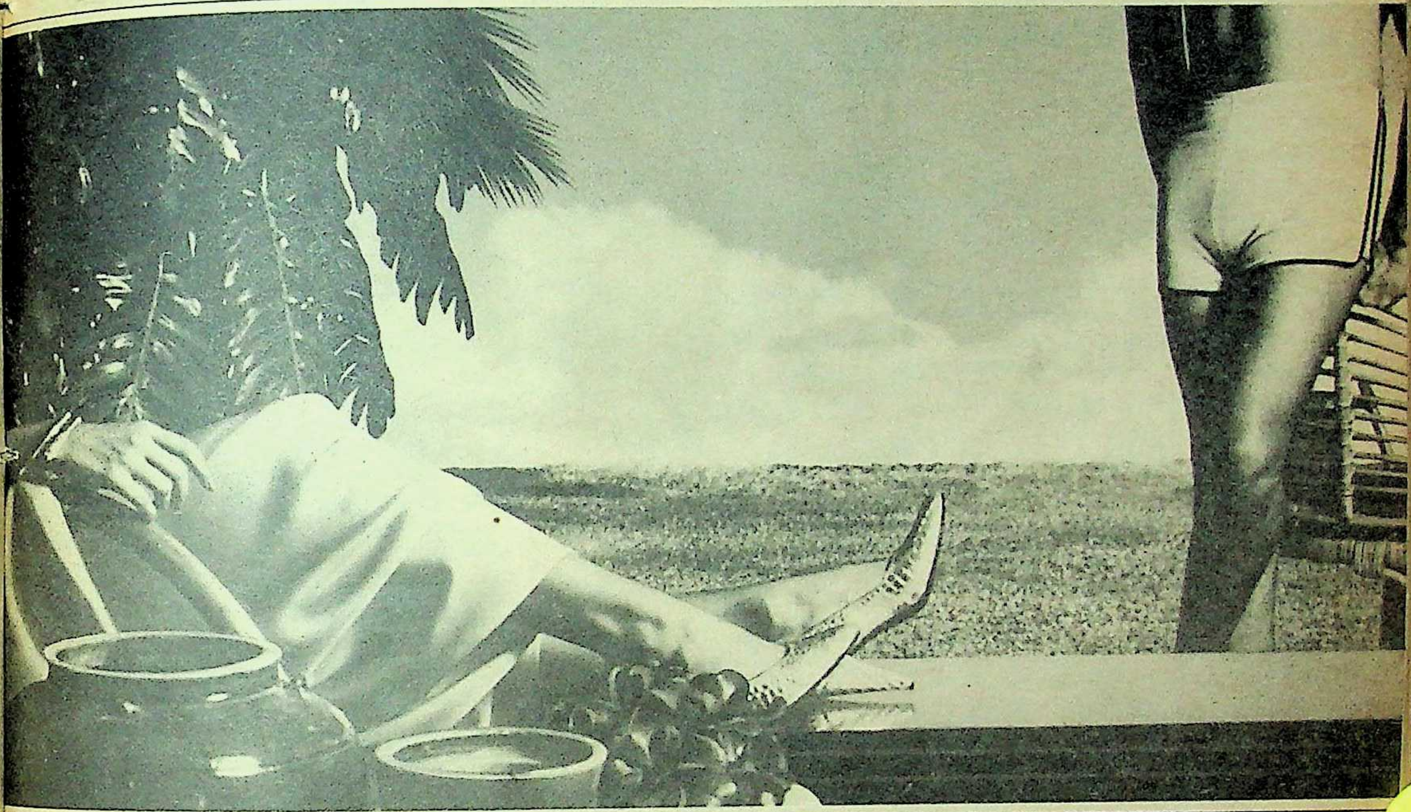

क्या कहा, कौनसी और लड़कियां?
सुनु ज़रा!
आज सुबह जब
मैं दौड़ने निकला तो...
हाय राम,
तुम यह पहन के दौड़ने गये थे?
और लडकियां मुझे
देख रहीं थीं घूर-घूर के!
और तुम्हे लगा कि
तुम हीरो हो, है न?
ब्रान्डो होगा तो उसके
चाहनेवाले भी होंगे.
हटो, मैं उन जैसी नहीं, मैं चली!
ए, आओ भी.
किसलिए?
जाते-जाते ज़रा...
जाओ-जाओ
अकेले-अकेले दौड़ लगाओ.

VIP
ब्रान्डो
नये अंदाज़ के अंडरवियर.

दिक्कत सिर्फ़ यह है, कि इसके चर्चे बहुत होते हैं।

Avenues HH 583 87R

अपट्रॉन पुरस्कार

वर्ष के लोकप्रिय टीवी सितारों का चुनाव कीजिए !

अपने चहेते कलाकारों को 'अपट्रॉन एवार्ड' से पुरस्कृत कराइए। देश भर से लोगों की राय जानकर विजेताओं का चुनाव किया जाएगा, नीचे दी गई प्रत्येक सूची में किसी एक नाम पर निशान लगाइए और फॉर्म जल्दी से भरकर भेज दीजिए। आप भी पुरस्कार जीत सकते हैं!

प्रतियोगिता दिलचस्प, आसान और एकदम मुफ़्त।
आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है. भारतीय टेलिविज़न कार्यक्रमों को और भी दिलचस्प बनाने में योगदान दीजिए.

पूरा फार्म ✂ काट कर आज ही भेजिए

मेरा प्रिय टीवी धारावाहिक

किस्से मिया बीवी के	1 ☐
निर्मला	2 ☐
उड़ान	3 ☐
तमस	4 ☐
कर्मभूमि	5 ☐
अदालत	6 ☐
महाभारत	7 ☑
इंतज़ार	8 ☐

मेरा प्रिय अभिनेता

आरिफ़ ज़करिया (अमर–कर्मभूमि)	1 ☐
रोहित ओहरी (दुग्गी–गणदेवता)	2 ☐
ओम पुरी (नत्थू–तमस)	3 ☐
धीरज कुमार (इन्स्पेक्टर–अदालत)	4 ☑
अंजन श्रीवास्तव (श्री वागले–वागले की दुनिया)	5 ☐
नसीरुद्दीन शाह (मिर्ज़ा ग़ालिब–मिर्ज़ा ग़ालिब)	6 ☐
रघुबीर यादव (मुंगेरीलाल–मुंगेरीलाल के हसीन सपने)	7 ☐
करन राजदान (श्री माथुर – किस्से मियाँ बीवी के)	8 ☐

मेरी प्रिय अभिनेत्री

दीपा साही (नत्थू की पत्नी–तमस)	1 ☐
अर्चना जोगलेकर (गुलाब देवी–कर्मभूमि)	2 ☐
प्रीति खरे (निर्मला–निर्मला)	3 ☐
रूपा गांगुली (दुर्गा–गणदेवता)	4 ☑
कविता चौधरी (कल्याणी–उड़ान)	5 ☐
रीता भादुड़ी (श्रीमती रेनु [illegible]–गुलदस्ता)	6 ☐
रंजीता (इला–आकाश गंगा)	7 ☐
प्रिया तेंदुलकर (श्रीमती माथुर–किस्से मियाँ बीवी के)	8 ☐

मेरा प्रिय सहयोगी अभिनेता

सुधीर जोशी (श्री जोशी–गुलदस्ता)	1 ☐
राजिन्दर गुप्ता (स्टेशन मास्टर–इंतज़ार)	2 ☐
केवल शाह (कृष्ण–महाभारत)	3 ☐
सुधीर पाण्डे ([illegible]–कर्मभूमि)	4 ☐
गोगा कपूर (कंस–महाभारत)	5 ☐
विक्रम गोखले (बाबूजी–उड़ान)	6 ☐
शफ़ी इनामदार (आधा सच आधा झूठ)	7 ☐
मुकेश खन्ना (भीष्म–महाभारत)	8 ☑

मेरी प्रिय सहयोगी अभिनेत्री

नीना गुप्ता (नवाब जान–मिर्ज़ा ग़ालिब)	1 ☐
शीला शर्मा (देवकी–महाभारत)	2 ☐
देबाश्री रॉय (सत्यवती–महाभारत)	3 ☐
अनीता राज (स्वाति–आकाश गंगा)	4 ☐
रूमा घोष (मुंगेरी की पत्नी–मुंगेरीलाल के हसीन सपने)	5 ☐
मंजु व्यास ([illegible]–महाभारत)	6 ☑
तन्वी आज़मी (बेगम उमराव–मिर्ज़ा ग़ालिब)	7 ☐
संगीता नायक ([illegible]–इंतज़ार)	8 ☐

मेरा प्रिय हास्य कलाकार

अंजन श्रीवास्तव (श्री वागले–वागले की दुनिया)	1 ☐
रवि बासवानी (आलोक शर्मा–[illegible])	2 ☐
करन राजदान (श्री माथुर–किस्से मियाँ बीवी के)	3 ☐
रघुबीर यादव (मुंगेरीलाल–मुंगेरीलाल के हसीन सपने)	4 ☑
सुधीर जोशी (श्री जोशी–गुलदस्ता)	5 ☐
शफ़ी इनामदार (आधा सच आधा झूठ)	6 ☐

मेरा प्रिय 'शीर्षक गीत

कर्मभूमि	1 ☐
मुंगेरीलाल के हसीन सपने	2 ☐
उड़ान	3 ☐
महाभारत	4 ☑
इंतज़ार	5 ☐
अदालत	6 ☐
किस्से मियां बीवी के	7 ☐
तमस	8 ☐

मेरा प्रिय बाल कलाकार

बेबी नवनीत बाली (बालिका कविता (कल्याणी)–उड़ान)	1 ☐
केवल शाह (कृष्ण–महाभारत)	2 ☐
शम्पा (बाल कृष्ण–महाभारत)	3 ☐
हंसराज (बलराम–महाभारत)	4 ☐
मास्टर अंतरिक्ष ([illegible]–आकाश गंगा)	5 ☐
केवल शाह (टिंकू–गुलदस्ता)	6 ☑

आलोचक की पसंद

सर्वोत्तम निर्देशक
सर्वोत्तम आलेख

नियम व शर्तें : ■ केवल 1988 में नेशनल नेटवर्क पर प्रसारित कार्यक्रम पात्र हैं ■ कोई प्रवेश शुल्क नहीं ■ केवल एक प्रविष्टि प्रति व्यक्ति ■ अधूरे फ़ार्म अस्वीकार कर दिये जायेंगे ■ निर्णायकों का फ़ैसला अंतिम ■ अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड, इसकी सहयोगी कंपनियों तथा इसकी विज्ञापन एजेंसियों के कर्मचारी भाग नहीं ले सकते ■ प्रवेश पत्र सभी अपट्रॉन कार्यालयों में भी उपलब्ध ■ पत्र-व्यवहार न करें।

पुरस्कार

अगर आप पुरस्कार पाना चाहते हैं तो पेश है एक रोमांचक प्रस्ताव. अपट्रॉन कलर टीवी को एक शब्द में 'ब्रांड' नाम दीजिए.

- प्रथम पुरस्कार : अपट्रॉन कलर टीवी
- 20 सांत्वना पुरस्कार : अपट्रॉन 2 बैण्ड ट्रांजिस्टर

ब्रांड नाम ____________________

नाम ____________________

आयु ____________ लिंग ____________

पता ____________________

____

प्रविष्टियाँ भेजने का पता है : **अपट्रॉन पुरस्कार.**
पोस्ट बैग नं. 4, पटेल नगर पोस्ट ऑफ़िस, नई दिल्ली 110 008

ULKA-D-UIL-391-HIN
MAYA–ALL

जल्दी कीजिए
प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि
15 अप्रैल 1989.

THE UPTRON AWARDS FOR GREAT TELEVISION PERFORMANCES

UPTRON

■ कम्प्यूटर्स ■ कम्यूनीकेशन सिस्टम्स ■ कॉम्पोनेंट्स ■ कंट्रोल सिस्टम्स ■ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ■ टेलिविज़न्स

इज्जत से खेलती राजनीति

राजस्थान के जोधपुर जिले के मारवाड़ जंक्शन कस्बे के ईसाई परिवार की कुमारी सोसन लायल के साथ कथित बलात्कार प्रकरण का राजनीतिकरण क्यों और कैसे हो रहा है?

सांकेतिक धरना 29-10-88
A.S.P. को बर्खास्त करो
POOLICE INVOLMENT IN THE REPECKS

राजनीतिक बदला: जब्बरसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में आयोजित धरना

अकरम खां

सोसन लायल

राजस्थान के जोधपुर जिले का एक कस्बा है मारवाड़ जंक्शन। दस हजार के लगभग इसकी आबादी है। आबादी में डेढ़ सौ परिवार मेव मुसलमानों के हैं। चार-पांच ईसाई परिवार यहां बसते हैं। हिंदू बहुल आबादी आले इस कस्बे पर राजनीतिक रूप से हमेशा भाजपा प्रभावी रही है। जोधपुर संभाग के खारची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले इस कस्बे में उस वक्त हड़कम्प मच गया, जब १९८८ के पाली लोकसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस-इ के उम्मीदवार को निर्णायक बहुमत इस कस्बे से हासिल हुआ। इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस-इ के कार्यकर्ताओं में एक दूसरे पर आरोप लगाकर चरित्रहनन का सिलसिला शुरू हो गया।

ईसाई परिवारों में से एक जार्ज लायल का परिवार मारवाड़ जंक्शन के थाने के पीछे वाली आबादी में बसता है। जार्ज लायल के एक पुत्र और दो लड़कियां हैं। तीनों किशोर वय के बच्चे वहीं के स्कूल में पढ़ते हैं। यह परिवार पिछले आठ साल से संकट में है।

लायल जंक्शन के लोको वर्कशाप में काम करते थे। वहीं पीतल चोरी के जुर्म में नौकरी से हाथ धो बैठे। शराब पीना उनकी आदत है। युवा बच्चों की परवरिश के लिए लायल की पत्नी श्रीमती शिरीन लायल ने तीन साल पूर्व एएनएम की ट्रेनिंग कर नागौर जिले के कोड गांव में परिचारिका के पद पर काम शुरू किया है। मारवाड़ जंक्शन से यह जगह काफी दूर है। परिणामस्वरूप बच्चों को अपने पिता के संरक्षण में ही रहना पड़ा है।

बलात्कार का आरोप: आरोप है कि इस परिवार की बड़ी लड़की कुमारी सोसन लायल के साथ पिछले साल के किसी माह में मारवाड़ जंक्शन ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल रहमान खां के पुत्र रहूफ खां और छोटू खां इंजिन ड्राइवर के पुत्र अकरम ने चाकू की नोक पर बलात्कार किया और अश्लील चित्र खींचे। इन चित्रों से भयभीत कर वे २४ अगस्त, १९७१ में जन्मी सोसन से मौका देखकर अपनी काम पिपासा बुझाते रहे। इसका भेद तब खुला बताते हैं, जब सोसन गर्भवती हो गयी और गर्भ गिराने के लिए प्रकरण के अभियुक्त अकरम ने कोई दवा सोसन को खाने के लिए दी। इस दवा के असर से सोसन को अत्यधिक रक्त स्राव हुआ और पिता को सारा किस्सा पता चल गया। बताया जाता है कि सोसन के ४५ वर्षीय पिता जार्ज लायल उसे लेकर अपनी पत्नी श्रीमती शिरीन लायल के पास नागौर जिले के कोड गांव पहुंचे। चिकित्सा के बाद पूरा परिवार मारवाड़ जंक्शन लौटा और १५ सितंबर, १९८८ को बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई।

मामला कुछ और: इस बीच पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की, तो मामला कुछ और ही नजर आया। इसके अनुसार दरअसल छोटू खां के पुत्र अकरम खां के साथ सोसन लायल का किशोर वय प्रेम था जो शारीरिक संबंधों में बदल गया और मां बनने की नौबत आ गयी। अकरम ने इन स्थितियों में सोसन से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता के सामने रखा, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में गर्भ गिराने के लिए दो हजार रुपए कुमारी सोसन के माता-पिता ने अकरम के पिता से लिए। पर वह मांग बढ़ती रही। ऐसे में अकरम के पिता छोटू खां ने सारा किस्सा दूसरे अभियुक्त रहूफ खां के पिता अब्दुल रहमान खां को बताया। मारवाड़ ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल रहमान खां ने जब जार्ज लायल को ऐसी हरकत से रोकने का प्रयास किया, तो लायल परिवार ने कथा को वह रंग दिया, जिसमें अकरम के साथ-साथ रहूफ खां को अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस में मामला जाने के बाद जिले के असंतुष्ट कांग्रेसी और भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग करने लगे।

मारवाड़ ब्लाक कांग्रेस-इ के अध्यक्ष के नाते अब्दुल रहमान खां जिले के प्रमुख कांग्रेसी विधायक एवं इंदिरा गांधी नहर मंत्री माधव सिंह दीवान और गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह से मिले। इन मंत्रियों ने पुलिस को जांच में सतर्कता बरतने के आदेश दिये, तो अपराधियों को सजा देने की मांग करने वालों ने इन्हें अपराधियों का पक्षधर करार दे दिया। इस बीच रहूफ के पिता अब्दुल रहमान के हाथ श्रीमती शिरीन लायल का एक पत्र लगा। इस पत्र के मजमून से साबित होता है कि सोसन की मां किसी और को भी सोसन के गर्भ के लिए जिम्मेदार मानते हुए पैसे वसूल कर रही थी। इस पत्र के आधार पर अब्दुल रहमान ने गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर श्रीमती शिरीन लायल पर अपनी पुत्री का गर्भ गिराने के आरोप में भादसं की धारा ३१८ के तहत कार्यवाही करने की अपील की। गृह राज्य मंत्री ने इस संदर्भ में १ दिसम्बर, '८८ को आदेश जारी किये।

इधर अब्दुल रहमान अपनी प्रतिष्ठा बचाने के प्रयास में लगे थे, उधर भाजपा नेता भैरों सिंह शेखावत ने अपने कार्यकर्ताओं के कहे अनुसार २३ नवम्बर, १९८८ को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपराधियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की। बहरहाल, गृह राज्य मंत्री द्वारा अब्दुल रहमान के आवेदन पर जांच के आदेश देने के बाद स्थितियां ऐसी बन गयी थीं, जिनमें श्रीमती शिरीन लायल की नौकरी खतरे में पड़ जाती। ऐसी स्थिति में आठ दिसम्बर को विपक्ष के नेता स्वयं श्रीमती शिरीन लायल और कुमारी सोसन लायल के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। सारी कथा का वर्णन हुआ और मुख्यमंत्री ने अपराधियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये। शेखावत ने कुमारी सोसन और उसकी मां को प्रेस के सामने पेश किया और स्थानीय अखबारों ने मारवाड़ जंक्शन गये बगैर सारी कथा आंसुओं में डुबोकर पाठकों के सामने परोस दी।

राजनीतिकरण: किशोर वय प्यार का यह किस्सा पाली जिले से चलकर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के अखबारों तक पहुंच गया। इसके लिए जिम्मेदार हैं पाली शहर युवक

कांग्रेस-इ के बागी नेता जब्बर सिंह राजपुरोहित। जब्बर सिह ने अपने शहर के युवक कांग्रेस-इ के नेताओं से नाराज होकर अपनी अध्यक्षता में पाली जिला युवक कांग्रेस एक्शन कमेटी का गठन सितंबर, '८८ में किया है। उन्होंने ५ दिसम्बर, '८८ को शपथ पत्र के साथ बयान जारी किया है कि ८ सितंबर, '८८ को जार्ज लायल अपनी पत्नी व बेटी सोसन लायल के साथ उनके पास पहुंचे और बताया कि मारवाड़ जंक्शन के ब्लाक कांग्रेस-इ अध्यक्ष अब्दुल रहमान के पुत्र रहूफ खां व अकरम पुत्र छोटू खां ने उनकी बेटी सोसन के साथ बलात्कार किया और उसके नग्न चित्र खीचे। जब लड़की गर्भवती हो गयी, तो अपराधियों ने लड़की का गर्भपात करवाया तथा उसे आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। शपथ पत्र में जार्ज लायल की ओर से दर्ज किया गया है कि अपराधियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जब वे मारवाड़ जंक्शन के थाने में गये, तो उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के स्थान पर उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। इसके बाद शपथ पत्र में सारी जिम्मेदारी एक्शन कमेटी के नेता जब्बर सिह ने ले ली। वे शपथ पूर्वक दर्ज करते हैं कि इसके बाद लायल परिवार को तत्कालीन एसपी के पास ले गये। वहां उन्होंने एएसपी महेंद्र कुमार गोविल के पक्षपाती रवैये पर नाराजगी प्रकट की और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निवेदन किया। एसपी मारवाड़ जंक्शन ने थानेदार को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये जो एएसपी गोविल के विरोध के बावजूद १५ सितंबर को दर्ज हुई।

जब्बर सिह अपने शपथ पत्र में यह भी दर्ज करते हैं कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी व उनके नजदीकी मंत्रियों के लोग तथा एएसपी गोविल आदि ने पीड़ित परिवार को मामले में समझौते हेतु डराना धमकाना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि इससे घबरा कर लायल परिवार वापस पाली आया और एसपी से शिकायत करने के बाद लड़की (सोसन) का मेडिकल करवाया व संबंधित गवाहों के बयान दिलाए। पर यहां भी मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों को गोविल ने प्रभावित किया, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। शपथ पत्र में आरोप लगाया गया है कि गोविल ने ३० सितंबर, १९८८ को अपराधियों को अपने पास शरण दी और गिरफ्तार नहीं किया।

जब्बर सिह अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि उक्त परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे लायल परिवार के साथ प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष व सांसद अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री राजेन्द्र चौधरी तथा अन्य कई अफसरों से मिले, पर पीड़ित की किसी ने मदद नहीं की। शपथ पत्र में जब्बर सिह दुख के साथ दर्ज करते हैं कि वे दुखी होकर जयपुर के अकाल राहत मंत्री माधव सिह दीवान व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिह से एएसपी गोविल की भूमिका के संबंध में बताने गये। जब्बर सिह बयान करते हैं कि माधव सिह दीवान के निवास पर उन्होंने अपराधी रहूफ खां और अकरम को देखा, तो हैरान रह गये। जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि दोनों अपराधी माधव सिंह दीवान और लक्ष्मण सिंह के कई दिनों से मेहमान बने हुए हैं। फिर अपने शपथ पत्र में वे अपराधियों द्वारा दी गयी धमकी और एएसपी गोविल द्वारा डरा धमका कर लायल परिवार से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने की बात लिखते हैं। जब्बर सिह ईश्वर को साक्षी रख कर जारी किये गये इस बयान में कहते हैं कि उन्हें एएसपी गोविल ने उक्त दोनों मंत्रियों के हवाले से अपनी पार्टी का मामला बताते हुए चुप रहने की सलाह दी, पर वे नहीं माने। वे अपने बयान में कहते हैं कि श्रीमती शिरीन लायल के विरुद्ध गर्भपात का मुकदमा झूठा है और फिर इस नतीजे पर पहुचते हैं कि सरकार व प्रशासन उक्त अपराधियों को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है।

साक्षात्कार/ अकरम खां

सोसन को मैं पसंद करता था

सोसन बलात्कार कांड का मुख्य अभियुक्त २५ वर्षीय अकरम खां कुछ दिन पूर्व ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। 'माया' ने उसके कथित अपराध के संबंध में बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के अंश :

माया : *क्या बलात्कार का आरोप गलत है ?*

अकरम : *नहीं, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। सोसन को मैं पसंद करता था और सोसन मुझे। मैं पिछले दो साल से उसके घर आता-जाता था।*

माया : *और भी लोग आते थे वहां ?*

अकरम : *हां, आते थे। पर मैं ऐसा नहीं समझता था कि सोसन मेरे अलावा किसी और से बात भी करती होगी। मैंने बड़ी मदद की इन लोगों की, यह तो सब भूल गये।*

माया : *रहूफ का नाम तुम्हारे साथ कैसे जुड़ा है ?*

अकरम : *साहब यह सोच कर तो मैं भी हैरान हूं। वह बेचारा तो इस रास्ते से भी नहीं गुजरा। उसके लिए अखबार वाले ऐसी बात छाप रहे हैं। सोसन ऐसा कह रही है, समझ में नहीं आता।*

माया : *राज्य सरकार के मंत्री दीवान साहब और लक्ष्मण सिह को कब से जानते हो ?*

अकरम : *अभी बाईइलेक्शन हुए तभी से जानने लगा हूं। चुनाव में हमने खूब काम किया, तो ये लोग खुश हुए।*

माया : *कोई मदद की मंत्रियों ने ?*

अकरम : *हां, की साहब। पुलिस ने बेजा परेशान नहीं किया।*

माया : *अब क्या सोचते हो सोसन के बारे में ?*

अकरम : *साहब उससे अकेले में बात करना। वह कह देगी कि सारी बातें झूठी हैं। वह डरी हुई है। मैं तो शादी करना चाहता था, पर लायल नहीं माना। फिर मेरी शादी हो गयी।*

—ओ०सै०

जब्बर सिंह ने इसी तरह के शपथ पत्र श्री व श्रीमती लायल के भी जारी किये हैं, फर्क बस इतना-सा है कि उनमें बलात्कार के साथ-साथ अपराधियों द्वारा नंगी तस्वीरों की कीमत मांगने की बात जोड़ी गयी है। इन शपथ पत्रों में जब्बर सिह कांग्रेस-इ का सदस्य होने का दावा करने के बावजूद जयपुर पहुंच कर अपने दल के मुख्यमंत्री के पास नहीं गये। वे पहुंचे विपक्ष के नेता भैरों सिह शेखावत के पास और शेखावत इस परिवार को लेकर गये मुख्यमंत्री के निवास पर। मुख्यमंत्री ने अपने दल के कार्यकर्ता को गौण किया और विपक्ष के नेता की उपस्थिति को अहमियत देते हुए कथित अपराधियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिये। विपक्ष के नेता ने अपने पसंदीदा पत्रकारों को कांड से वाकिफ कराया और शपथ पत्रों व कुमारी सोसन के बयान के आधार पर अकरम तथा रहूफ को अखबारों ने अपराधी करार दे दिया।

खोजबीन : 'माया' ने वास्तविकता जानने के लिए मारवाड़ जंक्शन के लोगों को टटोला। वहां ज्ञात हुआ कि जार्ज लायल चोरी के अपराध में सेवा से अलग किये हैं। वे आदतन शराबी हैं और घर खर्च चलाने के लिए अकरम जैसे नौजवानों से उधार लिया करते थे। अकरम खां के पिता छोटू खां से 'माया' ने बात की, तो उनका कहना था, "जार्ज लायल और मेरा लड़का पारलिया फैक्ट्री में लोहे का सामान बनाने का काम करने साथ-साथ जाते थे। उनके बच्चे भी हमारे घर आते जाते थे। चार पांच साल से यही सिलसिला था। अकरम अपनी साइकिल पर जार्ज को बिठाकर फैक्ट्री ले जाता था और साथ ही वापस लाता था। लायल परिवार अकरम को बेहद पसन्द करता था। और पसन्दगी के बीच अकरम से लड़की के ताल्लुकात हो गये।" मारवाड़ जंक्शन में इंजिन ड्राइवरी करने वाले छोटू खां कहते हैं, "मुझे इस बात का पता साल भर पहले ही लगा था। मुझे पता लगा, तो मैं अपने बच्चे को कंट्रोल में करने की तय कर के उसके लिए रिश्ते तलाशने लगा। जून, '८८ में मैंने अकरम की शादी कर दी। इसके बाद लायल परिवार से उसके संबंध बिगड़ने लगे। फिर भी लड़की से ताल्लुकात बने रहे। पत्रों का लेना-देना होता। हमारा पड़ोसी है सूरज। यहीं रेलवे में फोर्थ क्लास है। उसके घर पर चढ़ कर लड़की झाले देती थी। चुपके-चुपके मिलते थे। हम लोगों ने जब यह देखा, तो अकरम से पूछताछ की। उसका कहना था कि उसके पिताजी का संदेश देने के लिए वह छत पर आकर इशारे करती है।"

अकरम की शादी के बाद छोटू खां के अनुसार जार्ज ने सोसन के हमल के लिए अकरम को जिम्मेदार ठहराया। यह जार्ज ने तब कहा, जब कुमारी सोसन को गर्भपात के लिए वे उसकी मां के पास छोड़ आये थे। छोटू खां का कहना था कि जब वे कहते कि मुझे लड़की से मिलाओ, तो जार्ज लायल का जवाब होता, तुम कुछ पैसे दे दो, मिलकर क्या करोगे। इसी बीच पारलिया फैक्ट्री के मालिक के

भाई लूमा राम के नाम से श्रीमती शिरीन लायल का एक पत्र आता है। लूमा राम अकरम का हम उम्र है, उसने पत्र को अकरम के साथ पढ़ा और रख दिया, जिसे अकरम अपने घर ले आया। इस पत्र को देखने के बाद छोटू खां पसोपेश में पड़ गये। उन्होंने जार्ज लायल से भी कह दिया कि अब तो सोसन ही बतायेगी कि हमल के लिए कौन जिम्मेदार है? 'माया' ने छोटू खां से जानना चाहा कि राज्य सरकार के मंत्री इस संकट की घड़ी में उनकी क्या मदद कर रहे हैं? वे बोले, "साहब यह लडके जरूर चुनाव के समय कांग्रेस-इ के झंडे लिए घूमते थे, हम तो उन्हें जानते तक नहीं।" पांच बच्चों के पिता छोटू खां के लिए यह अनुभव बड़ा कसैला रहा है। वे कहते हैं, "साहब मारवाड में हम लोग जैसे रहते आये हैं, उस माहौल में कुछ लोग गड़बड़ करने लगे हैं। समझ नहीं आता, यह सब क्या हो रहा है?"

कथित अपराधी अकरम खां और कुमारी सोसन लायल के घर के बीच रेलवे कर्मचारी सूरज सिंह का दो मंजिला मकान है। इस मकान में वे अपने को किरायेदार बताते हैं। 'माया' ने जब उनके घर जाकर सोसन बलात्कार कांड के बारे में जानना चाहा, तो वे जोधपुरी में बोले—"साहब यह लड़की मेरे घर की छत से उसे झाले देकर बुलाती थी। हम ठहरे पड़ोसी। मोहल्ले के हर बच्चे को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। बात बढी, तो मैंने जार्ज से कहा था। पर वह उल्टा मुझे बंदूक से मारने की धमकी देने लगा। अकरम से सोसन का ताल्लुक था। सोसन के घरवाले अच्छी तरह जानते थे। पर दूध देती गाय था अकरम। तब तो रोज होता था बुलाओ अकरम को बुलाओ।" फिर रुक कर बोले सूरज सिंह, "यह बेचारा रहूफ आंख भी नहीं उठाता। उसको भी फंसा दिया, नेताओं ने। मैं जानता हूं कि रहूफ से सीधा पूरे मारवाड़ जंक्शन में कोई नहीं है, लेकिन उसे ही फंसा दिया।"

'माया' को पता लगा कि जार्ज लायल अपने पास की गणपति प्रोवीजन स्टोर की मालिक श्रीमती कस्तूर बेन पंडित के छह सौ रुपए नहीं चुका पाये थे। घर में जब भी कोई कमी होती थी, अकरम के खाते से चीज आ जाती थी। फिर क्या वजह है कि अकरम और रहूफ को बलात्कारी के रूप में पेश किया गया है? इस सवाल का जवाब मिला मारवाड़ भाजपा के सिंधी पंडित नेताओं से। 'माया' ने जब उनसे पूरे कांड पर प्रकाश डालने को कहा, तो उनका कहना था, "रहूफ खां के पिता अब्दुल रहमान कांग्रेसी नेता के रूप में आने से पहले अपराधी रहे हैं। उन पर चोरी के मुकदमे थे। आज सत्ता के साथ मिलकर उन्होंने पूरे मारवाड़ जंक्शन में अपना आतंक बना रखा है।" 'माया' ने इन नेताओं से जानना चाहा कि रहूफ और अकरम पहले भी किसी अपराध में चर्चित हुए हैं? उनका जवाब था, "नहीं।" अकरम का आना-जाना जार्ज लायल के यहां था? नेताओं का जवाब था, "पता नहीं।" 'माया' का तीसरा सवाल था, "फिर आप उन्हें अपराधी कैसे करार दे रहे हैं? नेताओं का जवाब था, "लड़की खुद कह रही है।" यानी आरोपों की पुष्टि करने वाली पीड़ित कुमारी सोसन लायल ही एक मात्र गवाह है। अब्दुल रहमान खां की कांग्रेसी राजनीति को ठिकाने लगाने के लिए भाजपा के लोगों ने तैयार किया है उन्हीं के नजदीकी रिश्तेदार दूसरे अब्दुल रहमान को। इन अब्दुल रहमान को मात्र छह माह में ही भाजपा नेताओं ने मारवाड़ जंक्शन की भाजपा पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया है। इन रहमान साहब का कहना है कि अब्दुल रहमान और उनके लड़के मारवाड़ के नामी गुंडे हैं। उन्होंने नवंबर, '८८ को पुलिस महानिदेशक राजस्थान को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उनकी नाबालिग और अनपढ़ पुत्री के नाम से उनके लड़के ने फर्जी प्रेम-पत्र की फोटो कापी मारवाड़ में बांटी तथा उनकी पत्नी से एक हजार रुपया जबरन ले गये। भाजपा के अब्दुल रहमान का आरोप है कि कांग्रेसी अब्दुल रहमान अपने बदनाम बेटों का निकाह उनकी बच्चियों से करना चाहते थे। जब उन्होंने इनकार किया, तो बदनाम करने के लिए बच्ची के नाम से फर्जी प्रेम-पत्र मारवाड़ जंक्शन में बांट दिये गये। ठीक इसके विपरीत मारवाड़ जंक्शन के कांग्रेस-इ कार्यकर्ता अपने ब्लाक अध्यक्ष अब्दुल रहमान को हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक मानते हैं। कांग्रेस-इ ब्लाक अध्यक्ष अब्दुल रहमान का पुत्र रहूफ इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सोसन लायल बलात्कार कांड के अपराधी के रूप में जेल में बन्द था, जबकि मुख्य अपराधी कहा जाने वाला अकरम जमानत पर बाहर आ गया। राजनीति ने प्रेम-कथा के पात्रों को अपराधी बना दिया है, वहीं मंत्रियों को अपराधियों का पक्षधर बना अनावश्यक रूप से लज्जित किया है। फिर जिस प्रेस पर मामले की खुलासे की जिम्मेदारी थी, वे डेस्क पर बैठकर इसको या उसको बचाने अथवा फंसाने की फिक्र में लगे हैं।

—ओम सैनी

साक्षात्कार/ सोसन लायल

अकरम और रहूफ को पहले नहीं देखा

मारवाड़ जंक्शन के खारची रोड स्थित जार्ज लायल के रेलवे क्वार्टर में 'माया' ने सोसन लायल से साक्षात्कार किया। सोसन के माता-पिता उस दिन पाली शहर गये हुए थे। उसके साथ उसका भाई डेविड लायल और छोटी बहन सलोनी घर में मौजूद थी। बेखौफ थी सोसन। जब 'माया' ने अपना मकसद बताया और सवाल किये, तो उसके जवाब चौंकाने वाले थे। प्रस्तुत हैं,साक्षात्कार के कुछ अंश :

माया: ***तुम्हारे साथ यह सब कब और कैसे घटा?***

सोसन: *मई '८८ की बात है। मैं घर में अकेली थी। मेरे भाई-बहन इतवार का दिन था इसलिए, टीवी देखने गये हुए थे। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला, तो अकरम और रहूफ अन्दर आ गये। अन्दर से दरवाजा बन्द करने लगे। मैंने रोका, पर नहीं माने। फिर उधर खाट पर अकरम ने गिरा लिया और कुकर्म किया। रहूफ ने फोटो खींचे। फिर रहूफ ने कुकर्म किया।*

माया: ***कैसे कैमरे से खींचे थे फोटो?***

सोसन: *(फोटोग्राफर के कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा) ऐसे पलके वाला (फ्लैश) कैमरा था।*

माया: ***किस समय की बात है?***

सोसन: *सुबह की। (सोसन जिस कमरे को बता रही थी, वह घर के पिछवाड़े का कमरा था, जिसमें रोशनी कम थी। बगैर फ्लैश के फोटो संभव नहीं था।)*

माया: ***तुमने घरवालों को तत्काल क्यों नहीं बताया?***

सोसन: *मुझे कहा था कि अगर किसी से कहा, तो सबको फोटो बता देंगे। बस इसी से डर गयी और वे हर बार कुकर्म करते रहे।*

माया: ***अकरम को कब से जानती हो?***

सोसन: *मैंने तो पहली बार देखा था दोनों को ही।*

माया. ***फिर अकरम को प्रेम-पत्र किसने लिखे?***

सोसन: *मैंने तो नहीं लिखे।*

माया: ***स्वायत्त शासन मंत्री राजेन्द्र चौधरी से तुम लोग जोधपुर सर्किट हाउस में इस मामले की शिकायत के लिए मिले थे?***

सोसन: *हां, मिले थे। उन्होंने पाली एसपी और कलेक्टर को फोन भी किया था।'*

माया: ***तुम्हारी मां तो कहती है कि किसी मंत्री ने कोई मदद नहीं की?***

सोसन: *मम्मी कहती है...*

माया: ***जब्बर सिंह को कब से जानती हो?***

सोसन: *जब्बर सिंह अंकल ने हमारी इस केस में बड़ी मदद की है, तभी से जानती हूं।*

माया: ***जयपुर कौन ले गया था तुम्हें?***

सोसन: *जब्बर सिंह अंकल ले गये थे। शेखावत साहब और अखबार वालों से उन्होंने ही मिलाया था।*

माया: ***तुम्हारे बयानों के कारण अकरम और रहूफ को सजा हो सकती है?***

सोसन: *हां, मैं सच कह रही हूं। अकरम और रहूफ को मैंने पहले नहीं देखा।*

माया: ***यह लूमाजी वाला किस्सा क्या है?***

सोसन: *मुझे नहीं मालूम।*

सोसन लायल ने अपने बयानों में यह नहीं माना कि अकरम से उसकी पुरानी वाकिफीयत है। उसके चेहरे पर कहीं झूठ अथवा पीड़ा के भाव नहीं थे, *जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य कुछ और ही कथा कह रहे थे।*

—ओ०सै०

जसपुर कताई मिल में खूनी संघर्ष क्यों ?

आठ बेकसूर मजदूर क्यों और कैसे मारे गये ? वे कौन लोग हैं जिन्होंने पूरब-पश्चिम की भावनाएं भड़काकर जसपुर कताई मिल को हिंसा-प्रतिहिंसा की आग में झोंक दिया है ?

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
कताई मिल
जसपुर (नैनीताल)
UTTAR PRADESH STATE TEXTILE CORPORATION LTD
SPINNING MILL
JASPUR (NAINITAL)

क्षेत्रवाद का अड्डा : कताई मिल जसपुर, नैनीताल

गत १६ फरवरी को जसपुर कताई मिल में पूरब-पश्चिम के झगड़े में ८ निरीह मजदूरों का मारा जाना, नैनीताल की समृद्ध और शांत तराई में बढ़ते क्षेत्रवाद का नतीजा है। पहले पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और अब जसपुर कताई मिल में पूरबी और पश्चिमी गुटों के लोग खुलकर आपस में टकराये हैं। ६ करोड़ की लागत से बनी जसपुर कताई मिल काशीपुर से लगभग २० किलोमीटर दूर स्थित है। काशीपुर, मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी का संसदीय तथा विधानसभाई चुनाव क्षेत्र रहा है। इसी कारण तिवारीजी, तराई में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे इस क्षेत्रवाद से काफी दुखी हैं।

जसपुर में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे स्थानीय राजनीतिकों तथा कुछ अधिकारियों की स्वार्थवादी राजनीति रही है। १६ फरवरी को सुबह लगभग ७ बजे मजदूर नेता मुसाफिर यादव कताई मिल परिसर में स्थित अपने क्वार्टर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे। मिल के समीप ही उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वे मुख्यद्वार की ओर भागे। वहां खड़े सुरक्षा गार्ड रामवीर ने जब हमलावरों को गोलियां चलाते देखा, तो उसने गेट बंद कर दिया। हमलावरों ने गेट के पास ही मुसाफिर यादव को गोली मार दी। उस समय रात की पारी छूट रही थी और सुबह की पारी शुरू होनेवाली थी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मिल के सुरक्षा सलाहकार सुरेश प्रसाद शर्मा ने उस दिन अस्थायी सुरक्षा गार्ड रामबाबू को हटा कर रामवीर सिंह की ड्यूटी लगा दी थी। रामवीर पश्चिम गुट का था। सुरेश प्रसाद शर्मा और रामवीर सिंह दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है।

पहला शिकार : मुसाफिर यादव

प्रतिहिंसा की आग : मुसाफिर यादव, कताई मिल में काम करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों के गुट के नेता थे। वे जसपुर कताई मिल मजदूर यूनियन कार्यकारिणी समिति के भी सदस्य थे। पूरब और पश्चिम गुटों के नेताओं के बीच मिल यूनियन पर कब्जे को लेकर एक विवाद भी चल रहा था। जब पूरबी मजदूरों को पता चला कि उनके नेता की हत्या करने में पश्चिम गुट के लोगों का हाथ है, तो उनका खून खौल उठा। कुछ मजदूरों ने श्रमिक बस्ती पर हमला बोल दिया। एक घर में आग लगा दी। कई क्वार्टरों के दरवाजे तोड़कर पश्चिम गुट के मजदूरों को जबरन बाहर खींचकर उन पर फरसे, तमंचे, लोहे की छड़ों और लाठियों से प्रहार कर ४ मजदूरों को मार डाला और कइयों को घायल कर दिया। हिंसा का यह तांडव लगभग आधे घंटे तक होता रहा।

इसी बीच कुछ श्रमिक घायल मुसाफिर यादव को लेकर जसपुर थाने गये, जहां उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मुसाफिर यादव की मृत्यु हो गयी।

मुसाफिर यादव की हत्या के संबंध में पूरबी गुट के एक मजदूर नेता केवलधारी यादव ने जसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी जिसमें कताई मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बृजेश शर्मा, महामंत्री सत्येंद्रपाल सिंह, निर्मल शर्मा, सतीश शर्मा तथा मिल के टाइम कीपर बृजवीर सिंह के नाम अभियुक्त के रूप में दर्ज कराये गये। ये सभी पश्चिम गुट के मजदूरों का नेतृत्व करते हैं।

कताई मिल के मुख्य अधिशासी आरके माहेश्वरी कहते हैं, "जैसे ही मुझे मुसाफिर यादव के घायल होने की खबर मिली, मैंने उसे अस्पताल ले जाने के लिए जीप दे दी। साथ ही मैंने जसपुर थाने को फोन पर सूचना दी कि लेबर कालोनी में आग लग गयी है। कुछ मजदूर मर गये हैं। किंतु जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो सब कुछ शांत हो चुका था।" लेबर कालोनी में चार मजदूरों की लाशें पड़ी थीं। एक दर्जन से अधिक घायल मजदूरों को पुलिस ने अस्पताल भेजा, जिनमें से तीन ने दम तोड़ दिया। पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप चंद्र और परगनाधिकारी एके द्विवेदी घटनास्थल पर पहुंचनेवाले पहले अधिकारी थे। कुछ समय बाद सांसद सत्येंद्रचंद्र गुड़िया और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी वहां आ पहुंचे। मृतकों में अमरीश

आतंक: गश्त करती पुलिस

मैनेजमेंट का मौन: आरके माहेश्वरी

कुमार शर्मा, श्याम सिंह, चंद्रपाल, राजेंद्र, सुभाष व कमलपाल त्यागी थे। श्यामसुंदर, सौदावृक्ष सिंह और जिले सिंह इतने अधिक घायल थे कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा।

सूत उत्पादन और गुणवत्ता में अव्वल आने वाली जसपुर कताई मिल में यह सब क्यों और कैसे हुआ ? इसका जवाब पाने के लिए यहां यूनियन पर कब्जे के लिए पूरब और पश्चिम गुटों के श्रमिक नेताओं के बीच लंबे अर्से से चल रहे झगड़े को जानना होगा। यह झगड़ा भी समीपवर्ती काशीपुर कताई मिल के पूर्व मुख्य अधिशाषी आरडी शर्मा की देन है। शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश टैक्सटाइल कारपोरेशन के संयुक्त निदेशक हैं। वे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और सांसद सत्येंद्रचंद्र गुडिया के सबसे अधिक कृपापात्र हैं। जसपुर, काशीपुर, झांसी, मेरठ और संडीला स्थित कताई मिलें आरडी शर्मा के ही निरीक्षण में हैं।

झगड़े की बुनियाद: जसपुर कताई मिल में उत्पादन सन '८४ में शुरू हुआ था। १५०० मजदूरों को खपानेवाली इस मिल में जेबी महरोत्रा मुख्य अधिशासी बने। मजदूरों में ६० प्रतिशत पूरबी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के हैं। यही कारण है कि इन श्रमिकों को पूरबी और पश्चिमी कहा जाता है। पूरबी गुट के मजदूर नेता तथा सुलतानपुर पट्टी (जसपुर) टाउन एरिया के चेयरमैन हरीश नेगी का आरोप है, "जसपुर कताई मिल में पूरब-पश्चिम की लड़ाई आरडी शर्मा की देन है।" वामपंथी मजदूर नेता हरदासी लाल भी यही आरोप दोहराते हैं।

श्रमिकों तथा श्रमिक नेताओं का कहना है कि २६ फरवरी '८६ को काशीपुर कताई मिल में हुए श्रमिक आंदोलन में पीएसी ने लाठीचार्ज भी किया था। फिर १६ जून '८६ को सूत मिल कालोनी में घुस कर श्रमिक अवधेश सिंह की हत्या कर दी गयी थी। इसी के बाद भड़के श्रमिक आंदोलन के चलते १७ जून से ६ सितंबर '८६ तक कताई मिल बंद रही थी। इस दौरान लगभग ३०० मजदूरों की छंटनी भी की गयी। चर्चा है कि इस दौरान आरडी शर्मा ने जसपुर कताई मिल के मुख्य अधिशासी जेबी महरोत्रा से कुछ मजदूरों की मांग की थी। महरोत्रा ने यह कह कर इनकार कर दिया था कि उनकी मिल का उत्पादन प्रभावित होगा। ७ जुलाई '८७ को आरडी शर्मा ने राजपाल नामक मजदूर को बुलाया था। ९ जुलाई को उसकी लाश सूती मिल के पास ही स्थित डिग्री कालेज से लगी नहर की पुलिया पर मिली थी। राजपाल के पिता छोटे सिंह ने आरडी शर्मा को अभियुक्त बताया था, पर पुलिस निष्क्रिय रही।

इसी के बाद शर्मा ने काशीपुर कताई मिल के बृजेश शर्मा को सहायक फिटर के पद पर जसपुर कताई मिल में रखवा दिया। पूरबी गुट के मजदूर नेताओं का आरोप है कि बृजेश शर्मा को ट्रायल में तीन बार असफल होने के बावजूद दबाव में आकर महरोत्रा ने मिल में रखा था। बृजेश शर्मा सांसद सत्येंद्रचंद्र गुड़िया के खास आदमी माने जाते हैं। गुड़िया को इन्होंने ही मिल मजदूर यूनियन का संरक्षक बनाया था। बृजेश शर्मा के आने के पूर्व पूरबी गुट का राजा राम मिल मजदूर यूनियन का अध्यक्ष था। धीरे-धीरे यूनियन पर पश्चिम गुट काबिज हो गया। इसके बाद मुख्य अधिशासी जेबी महरोत्रा को इतना आतंकित किया गया कि उन्होंने अपना तबादला झांसी करा लिया। मिल में १२ अगस्त '८८ को गठित यूनियन इंटक की थी। इसमें पूर्वी मजदूरों के बहुमत की उपेक्षा कर कार्यकारिणी में मात्र २ सदस्य पूरबी गुट से रखे गये। पदाधिकारियों में मात्र मोहन सिंह (उपाध्यक्ष) पूरब के थे। एक वर्ष का यूनियन का कार्यकाल पूर्ण होने पर पूरब के मजदूर चुनाव की मांग करने लगे। मजदूरों से प्रतिमाह लिए जानेवाले चंदे का डेढ़ लाख रु० से अधिक फंड यूनियन के पास जमा था, जिसे बृजेश शर्मा मनमाने ढंग से खर्च कर रहे थे। दशहरे के पूर्व दोनों गुटों में जमकर संघर्ष हुआ। पूरबी गुट, यूनियन का चुनाव कराने का पक्षधर था, जबकि बृजेश शर्मा और उनके समर्थक चुनाव कराने के विरोध में थे। इसी के बाद मुसाफिर यादव ने मजदूरों से चंदा लेना खुद शुरू कर दिया। बाद में इस मामले में अदालत में सुलह हो गयी, पर मारपीट और पार्टीबंदी जारी रही। इसके पूर्व ८ अगस्त '८८ को भी जसपुर बाजार में राम बढ़ाई, नारदमुनि, रामअवध को मारा-पीटा गया था। उसी रात विरोधी गुट ने मिल के अंदर ड्यूटी पर तैनात द्वारका, मुनव्वर अली और परमहंस को पीटा था। बृजेश शर्मा का विरोध मजदूर इसलिए भी करते थे, क्योंकि वे काशीपुर में रह कर राजनीति करते थे और उनकी ड्यूटी मिल में स्वतः लग जाती थी। इतना ही नहीं, कताई मिल परिसर में मजदूरों के लिए १७७ पक्के क्वार्टर हैं। पहले अधिकांश क्वार्टर पूरबी मजदूरों को मिले हुए थे। पश्चिम गुट के यूनियन पर हावी होने के बाद उन पर पश्चिम के मजदूरों का कब्जा हो गया। पूरबी मजदूर २५५ कच्चे झोंपड़े बना कर उनमें रहने लगे थे।

अप्रैल '८८ में आरके माहेश्वरी कताई मिल के मुख्य अधिशासी बनें। उनके साथ भी मजदूरों ने दुर्व्यवहार किया। काशीपुर उपचुनाव में पराजय के बाद आरडी शर्मा को वहां से हटा कर उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स कारपोरेशन का संयुक्त निदेशक नियुक्त कर दिया गया। जसपुर कताई मिल के

झगड़े के जन्मदाता : आरडी शर्मा

अधिकार क्षेत्र में आते ही शर्मा ने वहां नियमित रूप से आना शुरू कर दिया। ५ फरवरी '८६ को कताई मिल में आकर उन्होंने मुसाफिर यादव और मोहन सिंह को बुला कर २० फरवरी '८६ तक यूनियन का चुनाव करवाने का वायदा भी किया। मोहन सिंह का आरोप था, "शर्मा ने पहले धमकी दी और यहां तक कहा, "तुम दोनों को जिंदा रहना है या नहीं ?" क्योंकि शर्मा चाहते थे कि बृजेश शर्मा को ही अध्यक्ष बना रहने दिया जाये, जबकि पूरब के मजदूर इसके लिए कतई तैयार नहीं थे।"

मुसाफिर यादव और बृजेश शर्मा १४ फरवरी की रात आरके माहेश्वरी से मिले थे। माहेश्वरी ने 'माया' को बताया, "उन दोनों ने मुझसे आकर कहा था कि यूनियन का चुनाव करना है। मैंने कहा, करा लें। यह मैनेजमेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।"

इस झगड़े का एक कारण यह भी है कि मिल के नियमों में यदि कोई मजदूर दो बार आकर बिना काम पाये खाली लौटता है, तो तीसरी बार उसे काम अवश्य दिया जाता है। यूनियन के नेता अपने लोगों के नाम दर्ज करा लेते थे, जिससे पूरब के मजदूरों में असंतोष पनपा था। मिल में ट्रेनिंग पानेवाले मजदूर की दिहाड़ी मात्र पांच रुपए है, अतः उनमें भी रोष था।

आतंक, रोष बरकरार : झगड़े के बाद से मिल में उत्पादन ठप पड़ा है। मिल के अधिकारियों का कहना है कि मजदूर भयवश काम करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन १७ फरवरी को पीएसी ने श्रमिक बस्ती में रह रहे मजदूरों को घरों से निकाल कर बुरी तरह पीटा। इसी के बाद मजदूरों ने भागना शुरू कर दिया है। पुलिस ने २२ पूरबी मजदूरों को बलवे और हत्या के आरोप में नामजद किया है। अधिकांश गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में मिल के मुख्य अधिशासी आरके माहेश्वरी को भी निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर अमरोहा कताई मिल से बीजी नायर को नियुक्त किया गया है।

जसपुर थाने के प्रभारी डालचंद गोले ने १६ फरवरी को सरकारी रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली। काशीपुर से विधायक अकबर अहमद 'डम्पी' का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जेल भेजने तथा निलंबित करने की धमकी के अतिरिक्त मानसिक प्रताड़ना भी दी थी। बताया जाता है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने काशी (कडेश्वरी) में लगभग ४५ एकड़ जमीन कौड़ियों के मोल खरीदी है। इस खरीद-फरोख्त में काशीपुर कताई मिल के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इसी कारण पुलिस उनके इशारों पर ही नाचती रही है। यह जांच का विषय है।

विधायक अकबर अहमद को शुरू में मिल परिसर में जाने ही नहीं दिया गया। वे पूरे प्रकरण के लिए आरडी शर्मा और सांसद गुड़िया को दोषी ठहराते हैं। उनका आरोप यह भी है कि काशीपुर में पुलिस अधिकारी गुड़िया के इशारे पर ही थानेदार नियुक्त करते हैं।

इस संबंध में 'माया' ने सांसद सत्येंद्रचंद्र गुड़िया से बात करनी चाही, तो वे यह कर टाल गये कि 'आप मौका मुआयना कर लें।' नैनीताल के जिला परिषद अध्यक्ष आरपी जोशी ने इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक प्रक्रिया बताया। १६ फरवरी से ही जसपुर कताई मिल परिसर में डेरा डाले आरडी शर्मा ने 'माया' से बातचीत के दौरान अपने ऊपर लगाये गये सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। जसपुर कताई मिल में हुए इस रक्तपात की जांच परगनाधिकारी एके द्विवेदी कर रहे हैं। श्री द्विवेदी ने 'माया' को बताया, "यदि मिल के प्रबंधक मजदूरों के बीच चल रहे विवाद की जानकारी समय रहते प्रशासन को दे देते, तो इस घटना को टाला जा सकता था। कताई मिल से ८६ मजदूरों को भी निलंबित किया जा चुका है। उनके खिलाफ हत्या, बलवे और अन्य मामले पुलिस में दर्ज हैं। ये सभी मजदूर पूरब के हैं, इसी कारण लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है।"

जसपुरा कांड की गूंज विधानपरिषद और विधानसभा में भी हुई है। विधानपरिषद में इसे केपी तिवारी ने उठाया और विधानसभा में विधायक अकबर अहमद डंपी ने। दोनों सदनों में सरकार को इस मामले पर वक्तव्य देने का निर्देश मिला। विधानसभा में तो जसपुर कताई मिल को लेकर हुए हंगामे के कारण एक घंटे तक कार्यवाही भी रोकनी पड़ी।

मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा है, "यह घटना मेरे लिए वज्रपात के समान है।" यदि समय रहते क्षेत्रवाद की इस आग पर काबू न पाया गया, तो परिणाम निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक होंगे।

—निशीथ जोशी, जसपुर से

छाया : आरके राजू

साक्षात्कार/ आरडी शर्मा, संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम

सब बकवास है

'उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम' के संयुक्त निदेशक आरडी शर्मा पर आरोप लगाया जाता है कि जसपुर कताई मिल में हुआ संघर्ष उनकी ही देन है। शर्मा इसके पूर्व सन १९७२ से सन् '८८ तक काशीपुर कताई मिल के मुख्य अधिशासी रहे हैं। शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी के खास कृपापात्र माने जाते हैं। काशीपुर की राजनीति में भी उनका खासा दखल है। जसपुर कताई मिल के विश्रामगृह में आरडी शर्मा से 'माया' ने इस संबंध में बात की। उन्होंने 'माया' के प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सहज ढंग से दिये हैं। प्रस्तुत हैं, मुख्य अंश :

माया : *आप पर आरोप है कि जसपुर कताई मिल में जातिवाद की राजनीति आपकी देन है?*

शर्मा : *यह सब बकवास है। मुझे राजनीति से क्या लेना-देना ?*

माया : *क्या काशीपुर कताई मिल में आंदोलन के समय आपने जसपुर कताई मिल के मुख्य अधिशासी जेबी महरोत्रा से मजदूरों की मांग की थी, जिसके इनकार करने पर आपने बृजेश शर्मा को जसपुर कताई मिल में नियुक्त कराया था?*

शर्मा : *काशीपुर कताई मिल में मेरे कार्यकाल के दौरान आंदोलन हुआ तो जरूर था, पर कभी भी जसपुर कताई मिल से मजदूर मांगे जाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं। जहां तक बृजेश शर्मा की बात है, मेरी जानकारी के अनुसार उसका चयन जसपुर में ट्रायल के बाद हुआ था।*

माया : *आरोप है कि बृजेश शर्मा को ट्रायल में तीन बार फेल होने के बाद भी मेहरोत्रा ने राजनीतिक दबाव के चलते जसपुर कताई मिल में रखा था। इसमें आपने बृजेश की मदद की थी।*

शर्मा : *'ट्रायल' में एक बार असफल होने के बाद किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। यदि किसी ने ऐसा किया, तो गलत किया। जहां तक मेरी जानकारी है, यह मनगढ़ंत आरोप है। बृजेश शर्मा से मुझे इसलिए जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं भी पश्चिम का ही रहनेवाला हूं।*

माया : *क्या आपने ५ फरवरी '८६ को मुसाफिर यादव और मोहन सिंह से २० फरवरी '८६ तक यूनियन के चुनाव कराने का वायदा किया था?*

शर्मा : *मजदूर यूनियन के चुनाव से मेरा क्या वास्ता है? वह अपना चुनाव कराने के लिए आजाद है। मैनेजमेंट का चुनाव से कुछ लेना-देना नहीं होता है। यह श्रम विभाग और मजदूरों के मध्य की बात है।*

—नि०जो०

मंत्रियों का यात्रा भत्ता

उत्तर प्रदेश के मंत्री सरकारी खजाने से कैसे वसूली करते हैं ?

लोकपति त्रिपाठी

स्वरूप कुमारी बख्शी

गोपीनाथ दीक्षित

कोई कुछ भी कहे, उत्तर प्रदेश अपने मंत्रियो की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखता है। यह बात अलग है कि प्रदेश के आम नागरिक की औसत मासिक आय दो सौ रुपए है, लेकिन मंत्रियों को वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमास २५-३० हजार रुपए देने में भी कोई संकोच नहीं। यह चुनाव वर्ष है और इसमें तो प्रदेश के मंत्रियों में और भी आपाधापी है। प्रत्येक मंत्री यथासम्भव अधिक-से-अधिक रकम निकालना चाहता है। ठीक भी है, आखिर उसे चुनाव लड़ने के लिए पुष्कल राशि चाहिए। मंत्रियों और राज्यमंत्रियों को वर्ष में प्रति मंत्री ७१,७४८ रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। वर्ष १९८७-८८ में मंत्रियो के यात्रा भत्ते और जुलाई-अगस्त मास में प्रदेश से बाहर बिताये गये दिनों के किराये भत्ते का ब्योरा यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :

नरेन्द्र सिह को २,७०,२९७ रुपए का भुगतान किया गया (इसमें पैसे शामिल नहीं हैं)।

लोकपति त्रिपाठी नें एक वर्ष मे सरकारी खजाने से २,४०,४७० रुपए वसूले। सईदुल हसन ने भत्ते के रूप में २,२१,३१२ रुपए प्राप्त किये। इसी क्रम में हुकुम सिह ने, २,१५,७७६, ओम प्रकाश रिछारिया ने १,९९,७५९ रुपए, राज्यमंत्री संकटा प्रसाद ने १,९८,६७३ रुपए, राज्यमंत्री दीपा कौल ने १,९४,९९३ रुपए और राज्यमंत्री रामनरेश शुक्ल ने १,९०,७६१ रुपए प्राप्त किये। भोलाशंकर मौर्य ने १,८४,९२६ रुपए, गोपीनाथ दीक्षित ने १,७८,९१८ रुपए, अरुण कुमार सिंह ने १,७६,४४९ रुपए, राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान ने १,७५,७१२ रुपए, अम्मार रिजवी ने १,६२,००० रुपए, गौरीशंकर ने १,७०,९७० रुपए, मानपाल सिंह ने १,६९,९९६ रुपए, सीताराम निषाद ने १,५७,९३५ रुपए, प्रवीण कुमार शर्मा ने १,५४,९६४ रुपए, चेतराम गंगवार ने १,४७,३०२ रुपए, श्याम सूरत उपाध्याय ने १,४२,९३१ रुपए और प्रमोद कुमार तिवारी ने १,४१,७८० रुपए वसूले। राम औतार दीक्षित को १,३४,५२६ रुपए, शिवबालक पासी को १,३१,६४१ रुपए, निसार अहमद अंसारी को १,२७,२५४ रुपए, सिब्तेरजी को १,२७,१०५ रुपए, रामनाथ मुंशी को १,००,५९२ रुपए, सरस्वती अम्माल को १,००,४०५ रुपए, श्रीमती पद्मा सेठ को ९३,५७२ रुपए, उपमंत्री श्रीमती प्रमिला बधवार मेहरा को ८४,२९६ रुपए, जफरअली नकवी को ७२,९७२ रुपए, सुरेंद्र सिंह को ६६,९७९ रुपए, संजय सिंह को ६१,१३६ रुपए, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी को ५३,८६० रुपए का भुगतान किया गया। सबसे कम यात्रा भत्ता मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने वसूला। उन्हें इस मद में ३०,४७९ रुपए का भुगतान किया गया।

जुलाई-अगस्त, १९८८ में प्रदेश से बाहर बिताये गये दिनों के किराये भत्तें का ब्योरा—श्रीमती सुशीला रोहतगी ने प्रति छह दिन के बाद एक दिन राज्य से बाहर बिताया और फुटकर खर्च, विमान किराया और ट्रेन किराया के रूप में ५२,५७८ रुपए वसूले। नरेंद्र सिह ने २० दिन प्रदेश से बाहर बिताये और खर्च, किराये भाड़े के रूप में २४,९६६ रुपए प्राप्त किये। अन्य मंत्रियों को जितनी राशि का भुगतान किया गया उसका ब्योरा इस प्रकार हैं: अरुण कुमार सिंह १८ दिन २२,०५४ रुपए, गोपीनाथ दीक्षित ११ दिन १४,१२६ रुपए, श्रीमती दीपा कौल १० दिन १३,७९७ रुपए, सईदुल हसन १५ दिन १२,४०८ रुपए, लोकपति त्रिपाठी ४ दिन ११,३५५ रुपए, हुकुम सिंह १० दिन १०,७४८ रुपए, कोकब हमीद ७ दिन १०,०६० रुपए, श्यामसूरत उपाध्याय ६ दिन८,३९० रुपए, श्रीमती बेनी बाई ४ दिन, ७,१७८ रुपए, सुरेन्द्र सिंह चौहान ४ दिन ६,४५८ रुपए, कृष्णवीर सिंह कौशल ७ दिन ६,०४२ रुपए, चेतराम गंगवार ४ दिन ६,०१७ रुपए, नरेशचन्द्र ५ दिन ५,९३६ रुपए, गुलाब सिंह ९ दिन ५,८८८ रुपए, बिहारी लाल दोहरे ५ दिन ५,६६४ रुपए, सईदुज्जमा ६ दिन ५,६१९ रुपए, माताप्रसाद २ दिन ५,५८६ रुपए, सीताराम निषाद ३ दिन ५,२९२ रुपए, अजीत सिंह सेठी ८ दिन ४,८२० रुपए, बृजेन्द्रपाल सिंह यादव ४ दिन ४,२७६ रुपए, मुईद अहमद ३ दिन ४,१०६ रुपए, ओमप्रकाश रिछारिया ५ दिन ३,७५८ रुपए, बल्देव सिंह

अमरबेल जैसे फैले ये मंत्री

उत्तर प्रदेश के वर्तमान और पिछले मंत्री ऐसा मानते हैं कि जनता के सेवक बन कर 'जनता की संपत्ति' पर कब्जा किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि मंत्री की हैसियत से एक बार सरकारी मकान में घुस जाने के बाद वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये पिछले मंत्री न सिर्फ सरकारी मकान खाली करने से, वरन् किराया अदा करने से भी इनकार करते हैं। जो अब मंत्री हैं, वे उनके विरुद्ध शायद इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मंत्री न रहने के बाद वे भी यही रास्ता अपनायेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्रियों में सरकारी मकान का सबसे अधिक किराया २,३०,०७१ रुपए इंद्रजीत पर बाकी है। जयराज गौतम पर १,६६,७००, शिवानंद नौटियाल पर १,५९,९९२, कृष्णानन्द राय पर १,७०,८७७, दलजीत सिंह पर १,४८,६०५, धीरेन्द्र सहाय पर १,४५,९६२ और मुजफ्फर हसन पर १,००,००६ रुपए किराया बाकी है। जिन पर ५०,००० रुपए से एक लाख रुपए के बीच किराया बाकी है, उनमें सच्चिदानन्द बाजपेयी और संजय सिंह का नाम आता है। जिन पर ५० हजार रुपए से कम राशि बकाया है, उनमें लक्ष्मीरमण आचार्य, जफरअली नकवी, सुनील शास्त्री, प्रवीण कुमार शर्मा, सरस्वती अम्माल और हबीबुर्रहमान नोमानी शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि राज्य के पिछले छह मुख्यमंत्री और १६ पिछले मंत्री सरकारी बंगलों में गैरकानूनी कब्जा जमाये बैठे हैं और मकान खाली करने का नाम नहीं लेते। पूर्व मुख्यमंत्री इतने ईमानदार हैं कि किराया अदा करते हैं, पर जैसा ऊपर बताया गया है, पूर्व मंत्री किराया हड़प जाना अपना अधिकार या 'सेवा का पुरस्कार' समझते हैं। सरकार अब कह रही है कि सरकारी आवास पर उनका कब्जा गैरकानूनी माना जायेगा और अनधिकृत कब्जा हटाने की कानूनी कार्रवाई की जायेगी। बकाया किराया लगान की तरह वसूल किया जायेगा। मतलब यह है कि रकम वसूल न होने पर संपत्ति कुर्क करके नीलाम की जा सकती है। पर सरकार ने यह नहीं बताया कि इस तरह की धमकी कितनी बार दी गयी? नादार असामियों में सभी पार्टियों के नेता और मंत्री हैं। यदि कांग्रेसी नेता जनता की संपत्ति हड़प सकते हैं, तो गैरकांग्रेसियों की कुर्की नीलामी कैसे की जायेगी?

आर्य ५ दिन ३,७०६ रुपए, शिवबालक पासी ४ दिन ३,४०३ रुपए, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ४ दिन ३,२७४ रुपए, रघुवीर सिंह यादव ४ दिन, ३,२०० रुपए, श्रीनाथ सिंह ४ दिन ३,०५० रुपए, शिवनाथ सिंह कुशवाहा २ दिन २,६१८ रुपए, अजीत प्रताप सिंह २ दिन २,३३८ रुपए, श्रीमती रीना कुमारी ४ दिन २,३३६ रुपए, रामऔतार २ दिन १,५८८ रुपए, शैलेन्द्र कुमार १ दिन १,२१२ रुपए, श्रीमती हितेश कुमारी २ दिन ६११ रुपए, समरपाल सिंह २ दिन ६८५ रुपए, श्रीमती प्रमिला बधवार मेहरा ५ दिन, ६४० रुपए, संकठा प्रसाद शास्त्री २ दिन ५८० रुपए और निसार हुसैन २ दिन ५१५ रुपए।

इस प्रकार वर्ष १९८७-८८ में वेतन और यात्रा भत्ते के रूप में प्रदेश के मंत्रियों ने कुल मिला कर ७३,४४,०२३ रुपए और जुलाई-अगस्त १९८८ में प्रदेश से बाहर बिताये गये दिनों के खर्च के रूप में कुल मिलाकर ३,२६,८१० रुपए वसूल किये। निश्चय ही लोकतन्त्र गरीब देशों के लिए काफी महंगी व्यवस्था सिद्ध हो रही है। शायद यही वजह थी कि लोकतन्त्र के आलोचकों ने इस बारे में तरह-तरह के आक्षेप किये थे।

—रामपाल सिंह

"मेरी"
22 कैरट् स्वर्ण-आवृत जेवरों की चातुरी में है वीश्व नामी उत्तमता की प्रकृति। चमकीला सुन्दरी। सब की मन पसन्द, बेजाड़ रंगरूप में गारंटी जेवरों। मंगवाते वक्त जेवरों की संक्षा सूचीत करे। वी.पी.पी. खर्च अलग। मुफत केटलाग के लिए लिखे।

No.214
Rs. 75 50
No.209
Rs. 75 50
No.210
Rs. 75/50
No.9
Rs. 200/50
No.16
Rs. 200/50
No.120
Rs 40 50
No.121
Rs 40.50
No.123
Rs 40 50
No.124
Rs 40 50
No.126
Rs 40 50
No.127
Rs 40 50
No.27
Rs. 200 50
No.28
Rs. 225 50
No. 84. Rs. 50 50
No. 87. Rs. 50/50
No. 90. Rs. 50 50
No.93 Rs. 75 50
No.107
Rs. 75/50
No.110
Rs. 40/50
No.41 Rs. 150 50
No.42 Rs. 150/50
Rs. 50-50
Rs. 50 50
No.140
Rs. 50.50
No.193 Rs. 65 50

MERI GOLD COVERING WORKS
P.O. BOX : 1405, 14, RANGANATHAN STREET
T. NAGAR, MADRAS – 600 017

Move up... to McDowell's
Unmistakably No.1... McDowell's
McDowell's
The soda with spirit
MCD NO1 P2 2822

आक्रोश: चीनी नेतृत्व का पुतला जलाने के लिए

तिब्बत में चीन को चुनौती

ल्हासा में मार्शल ला लागू है। नगर की सड़कों पर अब आधुनिक अस्त्रों से लैस चीनी सैनिक गश्त करते हैं। स्वचालित अस्त्रों से लैस चीनी पुलिस आने-जाने वालों के कागज-पत्र देखने के बाद ही उन्हें जाने देती है। सब विदेशियों से कह दिया गया कि वे शुक्रवार, १० मार्च से पहले ल्हासा छोड़ दें। १० मार्च, १९५९ को तिब्बत में विद्रोह भड़का था। चीनी सेना ने बड़ी बेरहमी से उसे कुचल दिया था और दलाई लामा को तिब्बत छोड़ कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। १० मार्च, १९८९ को इसी विफल विद्रोह की ३०वीं वर्षगांठ थी। इस दिन तिब्बत में चीन से आजाद होने और अपने धार्मिक नेता दलाई लामा की वापसी के लिए भड़के दंगों के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की आशंका थी।

पृष्ठभूमि: शुरुआत ५ मार्च से हुई, उस दिन ल्हासा की मुख्य सड़क पर १३ बौद्ध भिक्षुणियां और भिक्षु इकट्ठे हुए। वे आजाद तिब्बत के झंडे हाथ में लिये हुए थे। वे भिक्षुणियां और भिक्षु तिब्बत की आजादी के नारे लगाते हुए एक जुलूस की शक्ल में चले। सामान्य तिब्बती नागरिक इस जुलूस में शामिल होने लगे। भीड़ में शामिल व्यक्तियों की संख्या हजारों में पहुंच गयी। तिब्बत की आजादी के नारे भी आसमान को चीरने लगे। लेकिन जुझारू तिब्बती केवल नारों तक ही सीमित नही रहे, उनका गुस्सा दुकानों, वाहनों और सरकारी भवनों पर भी उतरा। इसके जवाब में चीनी पुलिस ने अपना दमन चक्र शुरू किया और हताहतों की संख्या दिनोदिन बढ़ने लगी जिसकी परिणति हुई मार्शल ला में।

अशांति का नया दौर: तिब्बत में अशांति के ताजा दौर की शुरुआत सितंबर १९८७ से होती है। कहा जाता है कि २५ सितंबर को द्रेपुंग मठ के ऊपर एक इंद्रधनुष देखा गया और अगले दिन प्रातः भूचाल के हलके झटके महसूस किये गये। तिब्बती लामाओं ने इसे शुभ शकुन समझा। दलाई लामा इन्हीं दिनों तिब्बत के दौरे पर थे। इसी वर्ष जून मास में अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास करके १९५० में तिब्बत पर चीनी हमले की निंदा की थी। द्रेपुंग मठ पर इंद्रधनुष के दर्शन के बाद २७ सितंबर को इस मठ के लामाओं ने प्रदर्शन किया और तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारे लगाये। २९ सितंबर, १९८७ को तिब्बत के सेरा, द्रेपुंग और गंदेन मठ के धर्माचार्यों ने तिब्बती भाषा में लिखा एक पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भेज कर तिब्बत की आजादी की मांग की थी। एक अक्तूबर चीन का राष्ट्रीय दिवस है। उस दिन कुछ बौद्ध भिक्षु जोरवांग मठ के पास जमा हुए। प्रदर्शनकारियों में लगभग १०० लामा शामिल थे। उन्होंने एक हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन इस मठ की परिक्रमा की। ये सब आजाद तिब्बत के झंडे लिये हुए थे और आजाद तिब्बत के समर्थन में नारे लगा रहे थे। कहा जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने जोरवांग मठ के समीप बने थाने पर पथराव किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और चीनी पुलिस के बीच झगड़ा हुआ। एक चीनी फोटोग्राफर इस दृश्य के फोटो ले रहा था। इस फोटोग्राफर को पत्थर लगा और वह गिर पड़ा। इस पर चीनी पुलिसवाले क्रुद्ध होकर प्रदर्शनकारियों पर पिल पड़े। गोली चली, जिससे कम-से-कम छह तिब्बती, जिनमें दो लामा थे, मारे गये। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। लामाओं को पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए थाने ले जाया गया। इस झगड़े में चार चीनी भी मारे गये। इस प्रदर्शन के पांच दिन बाद ६ अक्तूबर को फिर तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया। इस दिन भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। कुछ तिब्बती मरे और भारी संख्या में गिरफ्तारी हुई।

तिब्बत की घटनाओं ने अमरीकी जनमानस को झकझोर दिया। ६ अक्तूबर, १९८७ को अमरीकी सीनेट ने एक प्रस्ताव पास करके तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के लिए चीन की निन्दा की। वाशिंग्टन स्थित चीनी दूतावास ने दलाई लामा की अमरीका यात्रा पर आपत्ति की थी। इसके बाद ल्हासा रेडियो ने दो तिब्बतियों को मृत्युदण्ड दिये जाने की सूचना दी थी। कुछ अमरीकी सांसदों का मत था कि चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों को इसलिए फांसी की सजा सुनायी, क्योंकि दलाई लामा अमरीका यात्रा पर आये हैं।

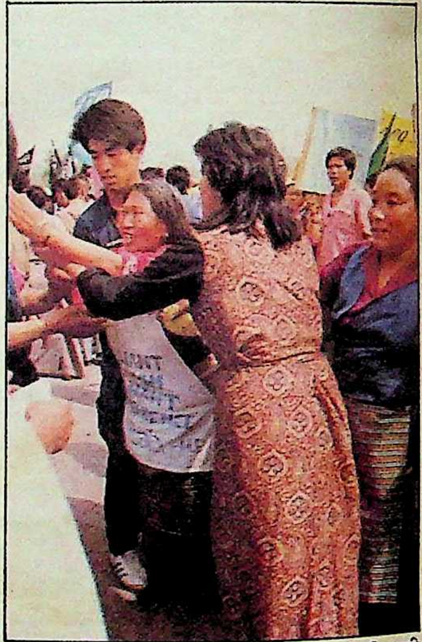

हमें आजादी चाहिए: दिल्ली में प्रदर्शनकारी तिब्बती

इस प्रदर्शन और झगड़े के बाद चीन ने तिब्बत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सेरा, द्रेपुंग और गंदेन मठ बंद कर दिये गये। लामाओं को उत्पीड़ित किया गया और उन्हें बाध्य किया जाने लगा कि दलाई लामा की निन्दा करें।

पणछेन लामा की अनसुनी चेतावनी: वर्ष १९८८ के आरम्भ में चीन में रह रहे पणछेन लामा तिब्बत के दौरे पर गये। उन्होंने कहा कि तिब्बत में दंगे इसलिए हुए, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने देश में कट्टर वामपंथी प्रयोग किये। चीनी अधिकारी

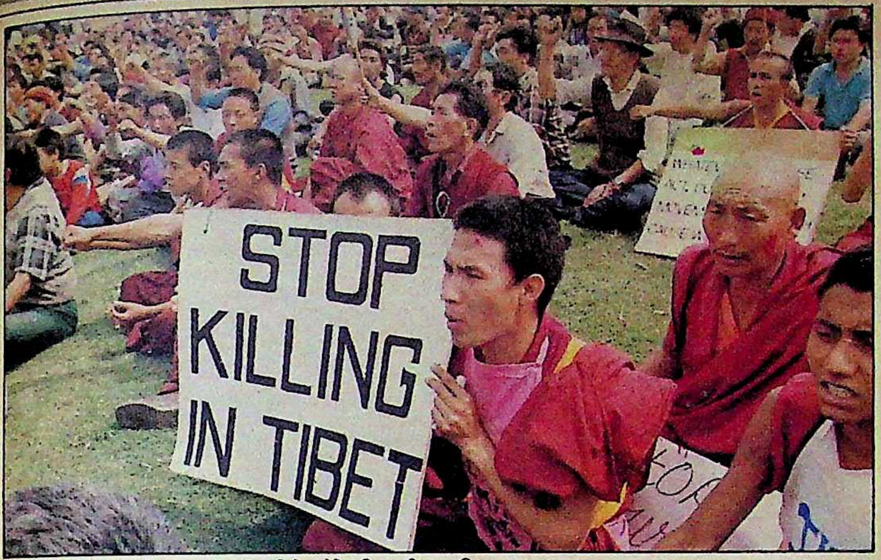

संघर्ष के लिए कटिबद्ध : धरना दिये बैठे तिब्बती नागरिक

तिब्बत की भावनाओं, उनकी धार्मिक आस्था, संस्कृति, भाषा आदि को नहीं समझते। वे नहीं जानते कि तिब्बत का विकास धर्म से जुड़ा है। पर पणछेन लामा की इस चेतावनी को चीनी अधिकारियों ने नहीं समझा। तिब्बत में उनकी दमनात्मक कार्रवाइयां जारी रहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि मार्च मास के प्रारंभ में जब तिब्बती जनता 'मोइनलाम ओएनयो' पर्व मनाती है, जिसके दौरान पूजा-उपासना के लिए मंदिर-मठों में भारी भीड़ होती है, ल्हासा में फिर दंगे भड़के।

५ मार्च, १९८८ को हुए प्रदर्शनों में हजारों तिब्बतियों ने भाग लिया। जोखांग मंदिर के पास सैकड़ों लामा और सामान्य जन एकत्र हुए और आजादी के नारे लगाये गये। चीन-विरोधी नारे भी लगे। एजेंसी फ्रांस के संवाददाता के अनुसार चीनी पुलिस ने फिर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलायी। कम-से-कम १० तिब्बती मारे गये।

तिब्बत में चीनी सेना और पुलिस के दमनकारी प्रयोग जारी थे कि दलाई लामा जून १९८८ में यूरोप की यात्रा पर गये। यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत के जो भाग काट कर किघाई, सीचुआन और सिनजियांग में मिला दिये गये हैं, उन्हें फिर तिब्बत में मिला कर तिब्बत को स्वशासी क्षेत्र घोषित किया जाये। चीन तिब्बत की विदेश नीति के प्रति जिम्मेदार रहेगा, पर तिब्बत को भी अधिकार होगा कि विदेशों से अपने गैरराजनीतिक संबंध बढ़ाये। दलाई लामा ने तिब्बत की समस्या हल करने के लिए 'एक देश दो व्यवस्था' का सुझाव रखा। चीन हांगकांग और ताईवान के साथ इसी प्रकार की व्यवस्था का समर्थक है। दलाई लामा ने तिब्बत को 'शांति क्षेत्र' बनाने के लिए एक क्षेत्रीय शांति सम्मेलन बुलाने का भी सुझाव रखा। पर चीन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि तिब्बत किसी प्रकार स्वायत्तता की उम्मीद नहीं कर सकता। उधर दलाई लामा का कहना है कि चीनियों ने यदि तिब्बत को खुशहाल बनाया होता, तो कोई शिकायत न होती।

दलाई लामा की अब भी कोशिश यह है कि चीन से समझौता हो जाये। चीन में सुधार की हवा चलने पर दलाई लामा ने चीन के नेताओं से सम्पर्क किया। १९८२ में दलाई लामा के बहनोई फुंतसोक तकला ने पेइचिंग में चीनी नेताओं से बात की थी। १९८६ में फुंतसोक तकला फिर पेइचिंग गये और उन्होंने चीनी नेताओं को सुझाया कि तिब्बती जनता को अपना भविष्य तय करने का अधिकार तो दिया ही जाना चाहिए। सितंबर-अक्तूबर १९८७ में दलाई लामा के छोटे भाई ग्यालो थोंदुप पेइचिंग गये, पर यह पता नहीं चला कि बातचीत के मुद्दे क्या थे ?

देंग का रुख : चीन के नेता देंग झियाओपिंग ने १९७९ में कहा था कि तिब्बत की पूर्ण आजादी और प्रभुसत्ता को छोड़कर किसी भी हल पर विचार हो सकता है। चीन ने पिछले दिनों स्वयं यह सुझाव रखा कि पेइचिंग के प्रतिनिधि जिनेवा में दलाई लामा से बात करने को तैयार हैं। पर ऐसा जान पड़ता है कि चीन के भीतर नेतृत्व के लिए जो टकराव हो रहा है, उसके परिणामस्वरूप तिब्बत के गतिरोध के पार जा पाना कठिन हो रहा है। यह भी हो सकता है कि तिब्बत की जनता चीनी अधिकारियों को दलाई लामा से समझौते को बाध्य करने के उद्देश्य से प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपना रही हो। एक अनुमान यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आ रहे परिवर्तन को देखकर तिब्बत की युवा पीढ़ी, जिसकी जड़ें विदेशों तक फैली हैं, देश के राजनीतिक भविष्य की बागडोर दलाई लामा को सौंपने के बजाय अपने हाथ में लेना चाहती हो।

जो भी हो, पर तिब्बत का हंसिया अब चीन के गले में फंसा है। देश के भीतर बढ़ती अशांति को वह आज भी बल प्रयोग से दबाना चाहता है। पर यही दमन तिब्बत की आग में घी का काम कर रहा है। सितंबर १९८७ में ल्हासा में जो आग लगी, वह यदि पुलिस या फौजी दमन से बुझायी जा सकती, तो कभी की शांत हो गयी होती।

—रामपाल सिंह

इतिहास के झरोखे में

चीन और तिब्बत का झगड़ा सदियों पुराना है। चीनी सेना ने ६ अक्तूबर, १९५० को तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। पर कब्जा और दमन के बावजूद इस झगड़े का अंत नहीं हुआ।

लगभग १००० वर्ष तक चले सतत संघर्ष के बाद चीन के मांचू किंग सम्राट ने १६६४ में तिब्बत पर अधिकार कर लिया था जो १९११ तक जारी रहा। तिब्बत पर कब्जा करने का चीनी उद्देश्य दलाई लामा को अपने सामने झुकाना था। इसके पीछे मंगोलों को भी दबाने का इरादा था, क्योंकि मंगोलों ने लामा धर्म स्वीकार कर लिया था। दलाई लामा को तोड़ने की चीनी योजना आज भी जारी है।

१९वीं सदी के अंतिम चरण में रूस के जार शासकों और ब्रितानी शासकों ने तिब्बत को प्रभावित करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों मध्य एशिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। १९१० में चीन के किंग सम्राट ने अपनी सेना तिब्बत भेजी। १९११ में चीन में क्रांति हुई और तिब्बत पर चीन का कब्जा समाप्त हो गया। १९१३ में दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। १९१४ में शिमला सम्मेलन में तिब्बत का प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से भाग लेने आया। १९५० तक तिब्बत स्वतंत्र रहा।

१९५० में चीन ने तिब्बत पर हमला किया। दलाई लामा का प्रतिनिधि पेइचिंग गया। वहां १७ सूत्री समझौता हुआ। दलाई लामा सरकार ने इस समझौते की कभी संपुष्टि नहीं की।

१९५९ में ल्हासा में एक विशाल सभा हुई। चीन से कहा गया कि वह तिब्बत से हट जाये। विद्रोह हुआ। चीनी सूत्रों के अनुसार ८७००० तिब्बती मरे। दलाई लामा ने एक लाख तिब्बतियों के साथ भारत में शरण ली। १९६६-७६ में चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई। ६००० तिब्बती मठ-मंदिर नष्ट कर दिये गये। १९८० के बाद से चीन ने मानना शुरू कर दिया कि उसने तिब्बत के मामले में गलती की है। ■

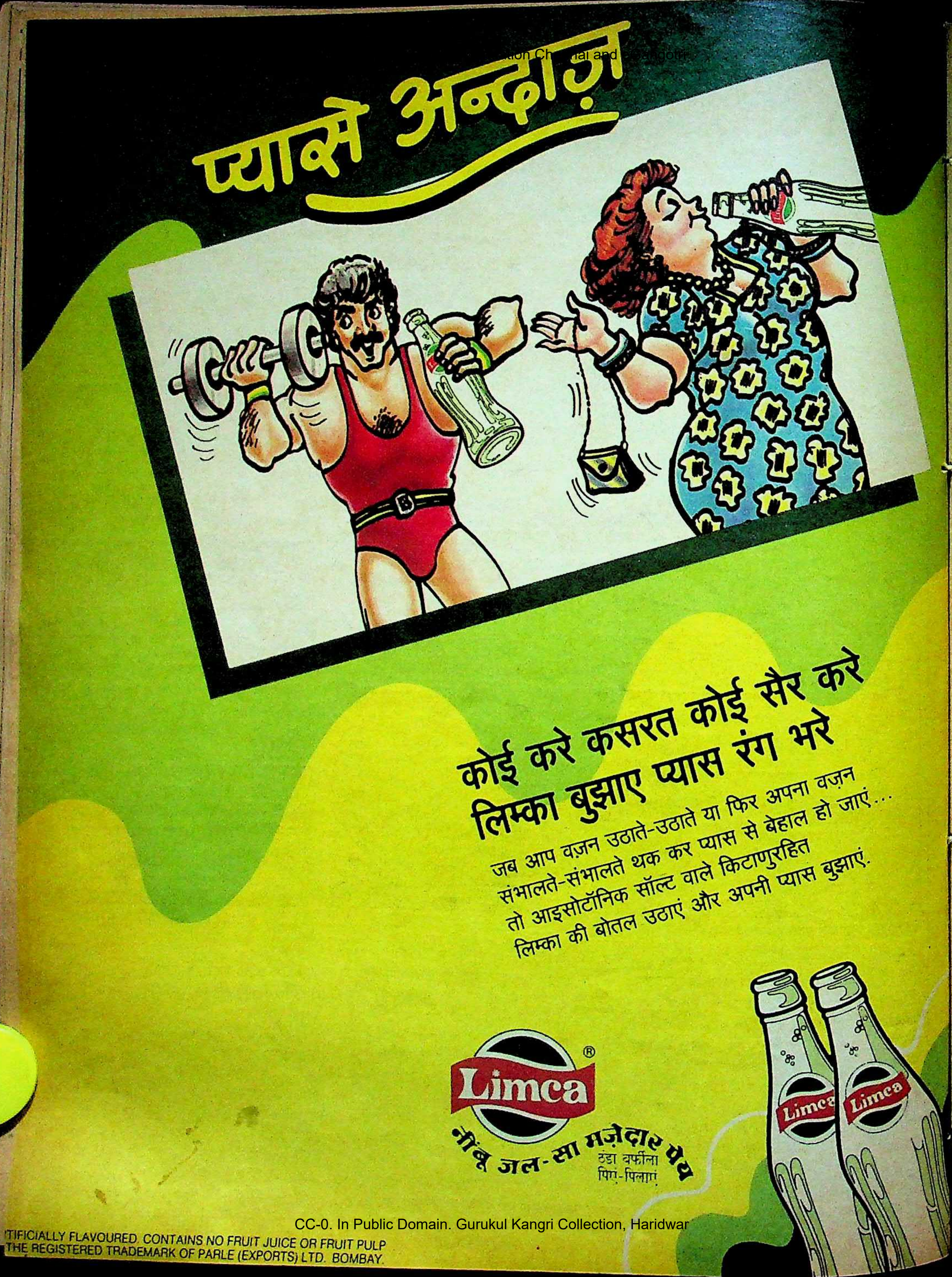
प्यासे अन्दाज़
Limca®
नींबू जल-सा मज़ेदार पेय
ठंडा बर्फीला
पिएं-पिलाएं
Limca
Limca

कोई करे कसरत कोई सैर करे
लिम्का बुझाए प्यास रंग भरे

जब आप वज़न उठाते-उठाते या फिर अपना वज़न
संभालते-संभालते थक कर प्यास से बेहाल हो जाएं...
तो आइसोटॉनिक सॉल्ट वाले किटाणुरहित
लिम्का की बोतल उठाएं और अपनी प्यास बुझाएं.

TIFICIALLY FLAVOURED. CONTAINS NO FRUIT JUICE OR FRUIT PULP
THE REGISTERED TRADEMARK OF PARLE (EXPORTS) LTD. BOMBAY.

पंजाब में नयी पहल का मकसद ?

हाल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंजाब मसले पर अपनाये गये उदारवादी नजरिये के बाद रिहा हुए जोधपुर बंदियों ने 'खालिस्तानी' नारों की गूंज से कांग्रेस-इ की नयी पहल के बेअसर होने के संकेत दिये हैं। इसके बावजूद कांग्रेस का दावा है कि उसकी नयी पहल पंजाब समस्या के हल में कारगर साबित होगी। पंजाब के लिए अपनाया गया राजीव गांधी का नया नजरिया और उसका उद्देश्य क्या है ?

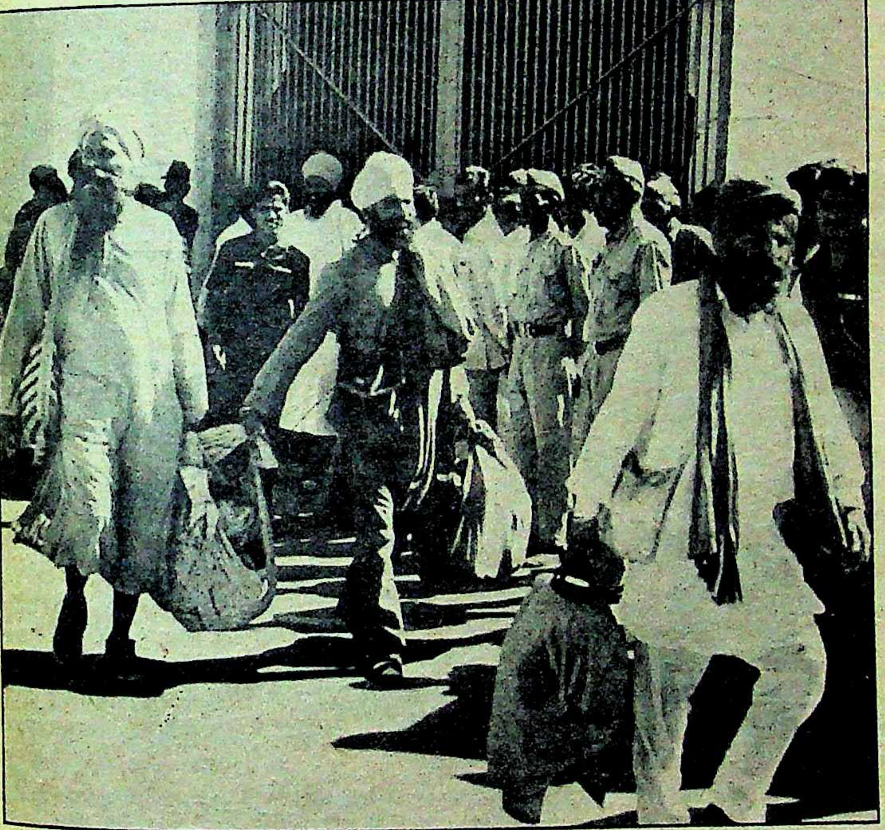

इतने दिनों बंद क्यों रखा ? : रिहा हुए जोधपुर बंदी

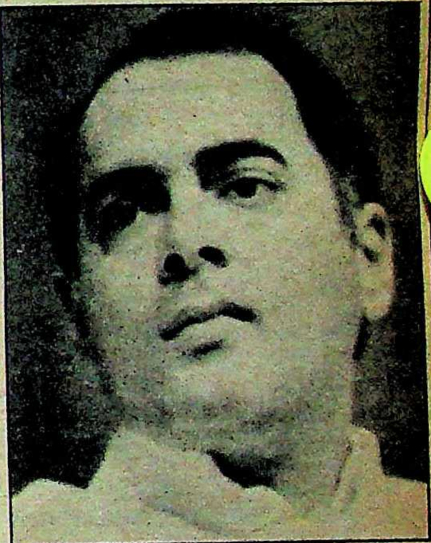

उदारवाद का सहारा : प्रधानमंत्री राजीव गांधी

२० मार्च को अमृतसर स्थित राजसांसी हवाई अड्डे पर पौने पांच वर्ष पश्चात घर लौटने वाले जोधपुर बंदियों के आगमन की प्रतीक्षा में आकाश की ओर उत्सुकता से टकटकी लगाये सुरक्षा अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अफसर मौजूद थे। कुछ क्षणों पश्चात वायु सेना का विशेष विमान उतरा और केसरिया पगड़ी पहने रिहा हुए बंदी भी। 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारों ने यकायक वातावरण की निस्तब्धता को छलनी कर अगवानी को आये अधिकारियों को पूर्णतया हतप्रभ और हताश कर दिया। यदि यह वारदात चार दिन पूर्व भी हुई होती, तो इस देशविरोधी नारेबाजी को कुचलने के लिए ये सुरक्षा अधिकारी और पुलिस अफसरान कोई भी कड़ा कदम उठाने में जरा भी संकोच न करते। किंतु उस दिन सब्र का कड़वा घूंट पीने के लिए सभी विवश थे। कारण प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा ३ मार्च को संसद में पंजाब समस्या के हल के लिए की गयी चार सूत्री पेशकश थी। इसके तहत पंजाब सरकार से अनुरोध किया गया था कि आपत्तिजनक भाषणों और लेखों के खिलाफ दर्ज किये गये मामलों को वापस ले लिया जाये। इसी सरकारी छूट का भरपूर लाभ पंजाब की धरती पर पांव रखते ही रिहा हुए बंदियों में से अनेक ने उठाया।

नयी पहल : नारा कदाचित खोखला ही था, किंतु इससे रिहा बंदियों की कुंठा, निराशा, हताशा, पीड़ा जख्म और क्रोध पूर्णतया उजागर हुए। "भला ये बंदी खुश और संतुष्ट कैसे होते ?" अकाली नेता बलवंत सिंह रामूवालिया ने 'माया' से सवाल करते हुए कहा, "पौने पांच वर्ष तक जिन्हें राष्ट्रद्रोह और देश के खिलाफ जंग आदि के गंभीर इलजाम में बिना मुकदमा चलाये जेल में बंद रखा जाये, तरह-तरह से यातनाएं दी जायें, जिनका पारिवारिक, सामाजिक जीवन चौपट हो जाये और जिनके आगे रोजी-रोटी का भयावह सवाल हो, उनके सीनों में जख्मों का रिसना और ऐसे फूट पड़ना अस्वाभाविक नहीं।"

केंद्र सरकार और पंजाब प्रशासन ने भी इसे इसी नजरिये से देखा है। इसी कारण इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई अथवा प्रतिक्रिया से न केवल परहेज किया गया, बल्कि रिहा हुए बंदियों के पुनर्वास में भरपूर मदद का आश्वासन भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर से कुछ बंदियों की रिहाई दो बार पहले भी हो चुकी थी। पहले, जसबीर सिंह रोड़े की रिहाई के साथ और दूसरे प्रधानमंत्री की गत सितंबर की प्रथम पंजाब यात्रा के ऐन पूर्व। गृह मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार इन रिहाइयों के बाद की जांच से साबित हुआ था कि जख्म कुछ समय में भर जाते हैं और खालिस्तानी नारे के तहट भटके लोग अंततः मुख्यधारा से जुड़ जाते हैं। चूंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो केंद्र सरकार यही आशा लगाये है कि इस बार भी राजनीतिक शतरंज की उसकी यह चाल जरूर शह में बदल जायेगी।

देर आये दुरुस्त आये के तहत समूचे देश और विपक्षी दलों ने जोधपुर बंदियों की रिहाई का स्वागत किया है। किंतु यह महत्वपूर्ण सवाल भी उठा है कि सरकार ने न तो इन बंदियों की लंबे समय की गिरफ्तारी का कभी स्पष्टीकरण दिया और न अब हुई रिहाई का। जाहिर है, बंदियों के निर्दोष होने का इससे अच्छा सबूत और क्या हो सकता है

कि लंबे अर्से की गिरफ्तारी के बाद भी उन पर सरकार ने कोई मुकदमा नहीं चलाया। भाजपा महासचिव कृष्णलाल शर्मा के अनुसार, "इसका एक ही अर्थ निकलता है कि इनको इतने दिनों तक बंदी रखने का कारण भी राजनीतिक था और आज छोड़ने का कारण भी राजनीति ही है।"

बंदियों की बहुप्रचारित रिहाई के अलावा सर्वाधिक जोर और प्रतिक्रिया पंजाब में आगामी मई में घोषित पंचायत चुनावों के मुद्दे पर हुई है। चार सूत्री पहल की संसद में घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पचायत चुनावों को लोकतंत्र और सामान्यीकरण की बहाली की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम बताया था। विडंबना यह है कि राजीय-लोंगोवाल समझौते के बाद निर्वाचित बरनाला सरकार को बर्खास्त करने का अलोकतांत्रिक कदम भी इसी सरकार ने उठाया था। जनता दल सांसद मधु दंडवते के अनुसार, "लोकतंत्र की बहाली की जो बातचीत आज की जा रही है, वह पंजाब में लागू राष्ट्रपति शासन की विफलता और नकारेपन की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति है।" अकाली नेता रामूवालिया ने जोड़ा, "बरनाला सरकार के समय की औसत ३ हत्याएं आज बढ़कर ६ पर पहुंच गयी हैं। तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ज्यूलियस रिबेरो ने स्वयं घोषणा की थी कि 'ए' श्रेणी के मात्र ३४ आतंकवादी थे। आज इनकी संख्या हजारों में नहीं, तो सैकड़ों में अवश्य है।"

मरहम लगाने का प्रयास : सामान्यीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक की वापसी और अशांत क्षेत्र में कानून के केवल गिने-चुने मामलों में प्रयोग के प्रावधान की व्यवस्था भी की गयी है। अधिकांश पर्यवेक्षक इसे पुलिस ज्यादतियों पर लगाम और आम जनता के घावों पर मरहम लगाने का प्रयास ही करार दे रहे हैं। ज्ञात रहे कि पंजाब में पुलिस 'आतंक' के किस्से सरेआम भी रहे हैं और केंद्रविरोधी माहौल का प्रमुख कारण भी। अमृतसर जिले के एक ग्रामीण नानक सिंह के अनुसार, "हालात इतने बिगड़ गये हैं कि दिन में आतंक पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता है, तो रात में सशस्त्र उग्रवादियों के रूप में। मकसद दोनों का एक ही होता है, लूटमार और जबरन वसूली।" निम्न वर्ग के पुलिसकर्मियों की बात तो दरकिनार स्वयं बटाला पुलिस एसएसपी गोविंद राम की कथित ज्यादतियों की शिकायत राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय तक पहुंचायी गयी।

पंजाब के विस्तृत दौरे से लौटे इन्द्र कुमार गुजराल ने 'माया' को बताया, "पंजाब प्रशासन एक ओर यदि उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियों से चिंतित है, तो दूसरी ओर पुलिस के बढ़ते अत्याचार और भ्रष्टाचार से। आतंक, अनिश्चितता, अव्यवस्था और आपाधापी का मौजूदा माहौल बरकरार रहे, ऐसा सभी भ्रष्ट पुलिसकर्मी चाहते हैं। कारण, इसी में वे फल-फूल सकते हैं।" ठीक विपरीत राय केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह की है। उनके अनुसार, "पंजाब में स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। आतंकवादियों को सफलतापूर्वक अलग-थलग कर दिया गया है, तथा आतंकवाद के समूल नाश के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे हैं।"

वर्तमान पैकेज के तहत जनता की सीधी शिरकत से बने जिला परिषदों के गठन द्वारा पंजाब की समस्याओं के समाधान में गतिशीलता आयेगी, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अनुसार, "जिलाधीश की अध्यक्षता में ये समितियां सलाहकार का भी काम करेंगी और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान भी।" इस नयी योजना के तहत विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों विशेषकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, गरीबों को आर्थिक सहायता देने, ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने आदि की भी व्यवस्था है। इसमें जनता को जोड़ने के प्रयास के अतिरिक्त सुरक्षा समितियों में भी उनका सहयोग और उनकी शिरकत अपेक्षित है। इस प्रकार आतंकवाद, पुलिस, अत्याचार, असुरक्षा और आर्थिक बदहाली से संत्रस्त और अलग-थलग लोगों को मूलधारा से जोड़ने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि राजीव सरकार लगभग चार वर्ष बाद इतने सकारात्मक कदम क्यों और किस लिए उठा रही है?

अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि सरकार को इस दौरान भलीभांति मालूम हो गया है कि पंजाब समस्या का समाधान 'बुलेट' नहीं 'बैलेट' है, 'पुलिस' नहीं 'जनता' है। अर्थात आतंकवादी हिंसा का जवाब पुलिस आतंकवाद नहीं, एकजुट प्रतिबद्ध जनता का अटूट मनोबल है। इस प्रकार सरकार का मंशा जनता को मुख्यधारा से जोड़कर पंजाब के रिसते घाव पर मरहम रखने के साथ ही अपनी नेकनीयती साबित कर 'अपना वोट बैंक सुरक्षित करना है।

अब तक हर पहल विफल : सिख विरोध

हाल के कदम आगामी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखकर उठाये गये हैं, ऐसा अधिकांश विपक्षी नेताओं का मत है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पिछले चुनाव घोषणा पत्र का मूल मुद्दा पंजाब समस्या को हल करने का था। जाहिर है कि आगामी चुनाव में उतरने के पूर्व, यदि वह समस्या का हल तो दूर, उसके लिए प्रयासरत और तत्पर नहीं दिखाई देगी, तो विपक्ष का तो तीखा प्रहार होगा ही, मतदाता भी उसे माफ नहीं करेगा!

विपक्ष को मात : कुछ पर्यवेक्षक इसे पंजाब में विपक्ष के हाथ से मुद्दा हथिया लेने का कांग्रेसी प्रयास भी बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले दिनों उसने चुनाव सुधार और मतदाता आयु घटाने के मुद्दे पर किया था। पंजाब की लाठी से तो विपक्ष ने केंद सरकार को सदैव ही मारा है। अतः पंजाब के मामलों में हाल की उसकी सक्रियता के फलस्वरूप कांग्रेसियों की नींद हराम होना लाजिमी था। उल्लेखनीय है कि हाल में राष्ट्रीय मोर्चे के दो शीर्ष नेताओं, हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल और तमिलनाडु के नये मुख्यमंत्री करुणानिधि के प्रयासों से ही सुदूर कोयम्बटूर जेल में कल तक के परस्पर विरोधी माने जाने वाले प्रकाश सिंह बादल और सुरजीत सिंह बरनाला की मुलाकात हुई थी। यही नहीं, अनेक टुकड़ों में विभाजित अकाली भी एकता प्रयासों में कदाचित पहली बार गंभीरता से जुटे। ऐसे में शासक दल की निष्क्रियता निश्चय ही नुकसानदेह साबित होती। विशेषकर इसलिए कि पंजाब समस्या के हल की मांग समूचा विपक्ष एक स्वर से करता रहा था। इसकी चर्चा चलने पर गृह मंत्री बूटा सिंह ने कहा कि जो देवीलाल कल तक पंजाब समझौते को नकारकर अपनी राजनीतिक रोटिया सेंक रहे थे, उनसे समस्या के हल की आशा करना ही हास्यास्पद है।

अमरीकी दबाव: राष्ट्रीय दबाव के साथ अंतरराष्ट्रीय और खासकर अमरीकी दबाव भी था, ऐसा प्रख्यात पर्यवेक्षक भवानी सेन गुप्त का दावा है। अमरीकी संसद में पंजाब को लेकर पेश एक प्रस्ताव ने भारत को भारी सांसत में डाला है। कारण, इसमें भारत को प्राप्त विशेष व्यापार सुविधाओं को समाप्त करने की मांग भी है। लगभग २० अमरीकी कांग्रेसजनों ने भारत को आगाह किया है कि यदि वह पंजाब मसले पर कोई ठोस और फौरी कदम नहीं उठायेगा, तो प्रस्ताव को रद्द करवाना मुश्किल होगा। अमरीकी प्रस्ताव में दो विशेष मांगें थीं। प्रथम, जोधपुर बंदियों की रिहाई। दूसरे, अप्रवासी भारतीयों की आवाजाही की सामान्य सुविधा की बहाली। इन्द्र कुमार गुजराल के अनुसार, "पंजाब की नयी पहल में इन दो मांगों की स्वीकृति को प्रमुखता देना स्वयं सिद्ध करता है कि सरकार ने अमरीकी दबाव के चलते ही घुटने टेके हैं।" स्मरणीय है कि इसी प्रसंग में कुछ माह पूर्व वरिष्ठ अमरीकी नेता स्टीफन सोलारेज ने न केवल भारत की यात्रा की थी, अपितु अमृतसर जा कर स्वर्ण मंदिर में भी घूमे-फिरे थे।

विपक्ष से तालमेल: प्रकाश सिंह बादल

पंजाब की नयी पहल यकायक उठाया गया कदम है, इसे सरकारी सूत्र नकारते हैं। गृह मंत्रालय के सूत्र के अनुसार, "इस दिशा में सरकार न केवल जागरूक रही है, अपितु समाधान ढूंढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत भी। आपरेशन ब्लैक थंडर से पहले जब स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों का मुख्य अड्डा बना हुआ था, कोई कारगर कदम उठा पाना असंभव था। आपरेशन ब्लैक थंडर के सफल अभियान से स्थिति में सुधार आने के साथ ही जनता के सामने एक ओर तो आतंकवादियों का घृणित चेहरा बेनकाब हुआ, तो दूसरी ओर सरकार को जनसमर्थन हासिल हुआ।"

स्थिति सुधरते ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गत वर्ष पंजाब की एक के बाद एक दो यात्राएं कीं। पहली सितंबर में, दूसरी अक्तूबर में। यही नहीं, एक सुनिश्चित दिशानिर्देश देने के लिए उन्होंने विदेशमंत्री पीवी नरसिंहाराव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उपसमिति भी गठित की। इसके प्रमुख सदस्यों में गृह मंत्रालय के तीनों सदस्य मंत्री बूटा सिंह, चिदंबरम और संतोष मोहन देव तो हैं ही, साथ में रक्षामंत्री केसी पंत, वित्तमंत्री एसबी चह्वाण, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी आदि भी शामिल हैं। इस समिति के क्रियाकलापों में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पंजाब के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय ने अहम भूमिका निभायी। समिति ने पंजाब मसले के सभी पक्षों पर गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन किया। विश्वसनीय सूत्रों ने 'माया' को बताया कि अंतिम फैसले के पूर्व हुई बैठक मध्यरात्रि को शुरू हुई तथा साढ़े चार घंटे तक चली।

केंद्र की चाल से वाकिफ: बरनाला

इसके बावजूद भाजपा अध्यक्ष आडवाणी पंजाब की नयी पहल को प्रधानमंत्री की जानी मानी तदर्थवादी नीति का ही एक अन्य कदम मानते हैं। उनके अनुसार, "वर्तमान पंजाब पैकेज को गौर से देखने पर पंजाब के विषय में उनकी (राजीव की) कोई एकमुश्त कारगर नीति दिखाई नहीं देती है और यह स्थिति राजीव गांधी के शासन काल के प्रारंभिक दिनों से उजागर है। मुख्य लक्ष्य या तो यश लूटना रहा है, या कोई फौरी लाभ।"

लालकृष्ण आडवाणी के अनुसार, "१९८५ में जो राजीव-लोंगोवाल समझौता हुआ उसकी वाहवाही तो बहुत हुई, लेकिन नतीजा सिफर निकला, क्योंकि समझौते से पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि अकाली दल के एक गुट से किये गये इस समझौते का उसके अन्य गुटों और हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी?" ज्ञात रहे कि देवीलाल ने केंद्र सरकार की इस भूल को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल कर विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को अभूतपूर्व पराजय दी थी। सतलज-यमुना जल के बंटवारे और चंडीगढ़ के हस्तांतरण का प्रश्न आज भी पंजाब-हरियाणा के मध्य विवाद का मुद्दा है।

१९८६ में पंजाब में पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर लगाम लगा कर तत्कालीन बरनाला सरकार के हाथ मजबूत करने के उद्देश्य से एक सुरक्षा पट्टी बनाने की योजना प्रस्तुत हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि स्वयं बरनाला सरकार इसके विरुद्ध थी। स्वाधीनता के ४० वर्षों के इतिहास में पहली बार संसद ने धारा २४९ के तहत सरकार को यह अधिकार सौंप भी दिया। किंतु उस पर अमल आज तक नहीं हुआ है।

सुरक्षा पट्टी के मसले की विफलता पर जब आडवाणी के आरोपों की ओर 'माया' ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, तो जवाब मिला, "इतने अव्यावहारिक मसले को आडवाणी क्यों उठा रहे हैं, जिसका प्रभाव न केवल १०२ सीमावर्ती गांवों पर पड़ेगा, बल्कि लाखों ग्रामीणों को बेघर कर देगा।" जवाब में आडवाणी बोले, "सुझाव मेरा नही स्वयं केंद्र सरकार का है। जाहिर है, उन्होंने प्रस्ताव पेश करते समय उस पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श नहीं किया था।"

विचित्र चाल: १९८७ में राजीव गांधी ने जो किया वह इससे भी ज्यादा विचित्र था। हरियाणा चुनाव के ऐन पूर्व लोकतंत्र की बहाली से बनी बरनाला सरकार को स्वयं बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी के दो महीने पहले ही बरनाला का गुणगान करते स्वयं राजीव गांधी ने ऐलान किया था कि महाराजा रंजीत सिंह के काल के बाद पंजाब को पहली बार इतना काबिल प्रशासक मिला है।

१९८८ में आपरेशन ब्लैक थंडर का सफल अभियान चलाया गया। लेकिन उसके बाद स्थिति का लाभ उठाते हुए पंजाब की समस्या हल करने के बजाय उसे और विषम बना दिया गया। इसके कुछ समय पहले ही सुशील मुनि और दर्शन सिंह रागी की गुपचुप मुलाकात में राजीव गांधी अपनी स्थिति जटिल बना चुके थे। स्वयं बातचीत कराकर बाद में भंडाफोड़ होने पर जिस प्रकार वे मुकर गये, उसने स्थिति को विवादास्पद भी बनाया, हास्यास्पद भी।

पंजाब समस्या के हल की सबसे विचित्र घटना जसबीर सिंह रोड़े की रिहाई और अकाल तख्त पर सरकारी समर्थन से उनकी ताजपोशी की रही। कारण, रोड़े का केवल संत भिंडरावाले का भांजा होना नहीं था, बल्कि देशद्रोह के आरोप में सुदूर विदेश में उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने जमीन-आसमान के कुलाबे मिला दिये थे। रिहाई का नतीजा अपेक्षित रहा। इसे सरकार की कमजोरी मान आतंकवादियों ने मौके का भरपूर लाभ उठाया। अकाल तख्त की जत्थेदारी संभालते समय सुरक्षाकर्मियों की नाक के नीचे न सिर्फ जाने-माने आतंकवादी नेताओं ने सरोपे ही भेंट किये, वरन्

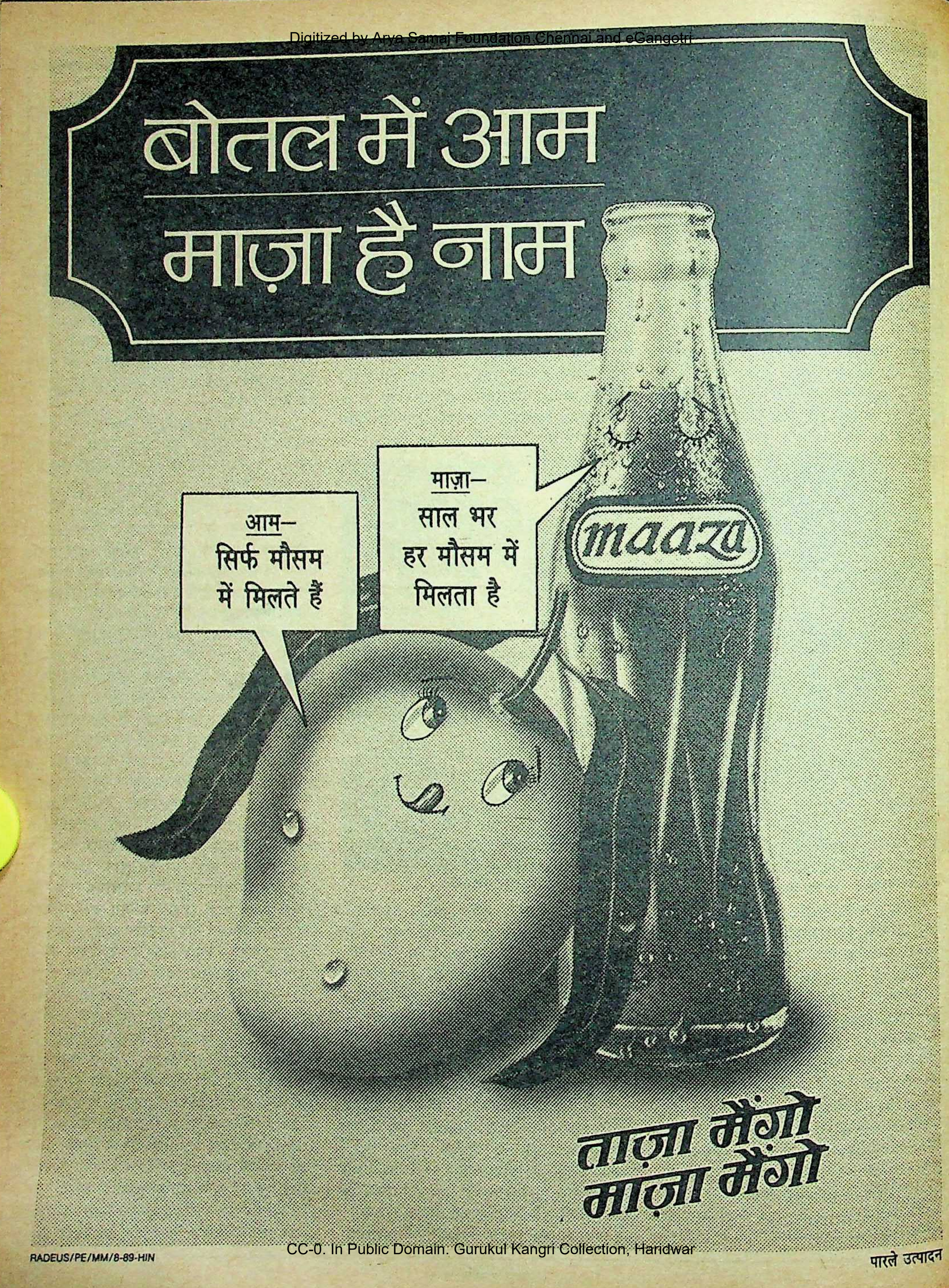
बोतल में आम
माज़ा है नाम
आम—
सिर्फ मौसम
में मिलते हैं
माज़ा—
साल भर
हर मौसम में
मिलता है
maaza
ताज़ा मैंगो
माज़ा मैंगो
RADEUS/PE/MM/8-89-HIN
पारले उत्पादन

]

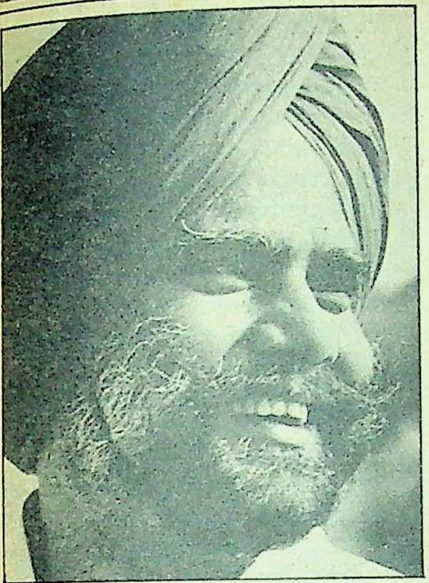

जख्म भरने की उम्मीद : बूटा सिंह

अपना विजय-समारोह बंदूक दाग कर और 'खालिस्तानी' नारे लगाकर मनाया। कुछएक ने तो मौका पाकर स्वर्ण मंदिर पर 'खालिस्तानी झंडा' भी फहरा दिया। गुजराल ने 'माया' से कहा, "यदि चमनलाल से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रोड़े की वापसी का खुला विरोध कर उसके मार्ग में रोड़े न अटकाये होते, तो आज जसबीर सिंह रोड़े जैसे लोगों का नियंत्रण मात्र स्वर्ण मंदिर में न होकर समूचे पंजाब पर होता।"

असली गुनहगार : उग्रवादी तत्वों को समर्थन व बढ़ावा देने में राजीव सरकार पहली नहीं। भिंडरावाले को पालने-पोसने और उसका कद ऊंचा करने का काम किसी अन्य ने नहीं, श्रीमती गांधी के छोटे बेटे स्व० संजय गांधी और उनके चहेते भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ही किया था। पंजाब में कांग्रेस के अविवेकपूर्ण कदमों की शुरुआत १९६७ में तब हुई, जब राज्य की अकाली-जनसंघ साझा सरकार को न केवल सांसत में ही डाला गया, बल्कि एक के बाद एक तीन बार गिराया भी गया। वह भी भिंडरावाले और जगजीत सिंह चौहान जैसे धार्मिक कठमुल्लाओं के सहयोग से। जानकार सूत्रों का दावा है कि १९७७ और १९८० के चुनावों में कांग्रेस को तरनतारन और अमृतसर की सीटों पर विजय कभी न मिली होती, यदि इसके लिए उसे भिंडरावाले का सहयोग और समर्थन एलानिया प्राप्त न रहा होता। यह दीगर बात है कि जब चिराग का यह धुआं जिन्न बन गया, तो कांग्रेस ने उससे पल्ला झाड़ने में ही अपनी खैर समझी। स्वर्ण मंदिर, जो आतंकवादियों का गढ़ बना था, पर ५ जून '८४ के सफल आपरेशन 'ब्ल्यू स्टार' से भिंडरावाले का भी सफाया न हो गया होता, तो यह विष वृक्ष और घातक सिद्ध होता।

निस्संदेह पंजाब में आज भिंडरावाले जैसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं, किंतु राज्य की स्थिति बद से बदतर हो गयी है। पंजाब समस्या की विडंबना यह है कि उसके कारण और समाधान की पक्ष-विपक्ष किसी ने भी गंभीरतापूर्वक चिंता नहीं की। हरेक अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में ही लगा रहा। पंजाब में धर्म और राजनीति का हमेशा से चोली-दामन का साथ रहा है। इसमें अपराधी और असामाजिक तत्वों की व्यापक घुसपैठ से स्थिति और बिगड़ गयी है। आग में घी का काम पाकिस्तान ने आतंकवादियों को निरंतर शरण, शह, प्रशिक्षण, पैसा और घातक हथियारों की आपूर्ति से किया है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली और बेनजीर भुट्टो की ताजपोशी ने स्थिति में सुधार की जो नयी किरण दिखाई थी, उसे प्रधानमंत्री बेनजीर के आश्वासन ने परवान भी चढ़ाया है। किंतु अब तक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, इसे अधिकारिक सूत्र भी स्वीकारते हैं। कारण, कदाचित यही है कि पाकिस्तान में कम से कम पंजाब हस्तक्षेप के मुद्दे पर बेनजीर से ज्यादा सेना की चलती है जिस पर अमरीका की सरपरस्ती है।

पंजाब समस्या के समाधान का कभी प्रयास नहीं किया गया यह कहना गलत है। कदम उठाये गये हैं लेकिन आधे-अधूरे और ठिठके हुए। नतीजतन मौका हमेशा हाथ से निकलता गया है। अवसर निकल जाने के बाद आयी सद्‌बुद्धि के चलते आज सभी मानते हैं कि स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाने का सबसे सुनहरा मौका वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भूनकर की गयी हत्या की वारदात थी। यदि उस समय फौरी और कड़ा कदम उठाया गया होता, तो स्थिति इतनी विकराल और विषम रूप धारण न करती। आपरेशन 'ब्ल्यू-स्टार' के पूर्व भी एक मांकूल मौका तब गंवाया गया, जब उदारवादी अकाली नेताओं को एकजुट कर भिंडरावाले को निष्प्रभावी करने का क्रोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

आपरेशन ब्ल्यू स्टार : आपरेशन 'ब्ल्यू स्टार' कार्रवाई गलत थी, यह भी नहीं कहा जा सकता। किंतु उसके बाद उभरे माहौल का भी समुचित उपयोग नहीं हुआ। पंजाब समस्या को नजदीक से देखनेवाले एक पर्यवेक्षक के अनुसार सरकार की क्षमायाचना की मुद्रा और तुष्टीकरण की नीति के कारण अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ। एक तो सरकार ने कड़ाई की जगह ढील दे दी। इससे आतंकवादियों का मनोबल भी बढ़ा और उन्हें स्वर्ण मंदिर के भीतर पैर जमाने का एक और मौका भी। पर्यवेक्षक ने अकाल तख्त की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा खर्च किये गये ६ करोड़ रुपए की मिसाल देते हुए बताया, "इस समूचे धन पर पानी फिर गया, क्योंकि जिस दिन अकाल तख्त मरम्मत के बाद उग्रवादियों के हाथ में पहुंचा, तो न केवल उन्होंने उसे तोड़ दिया, बल्कि सिखों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया भी। यदि यही धन गरीबों, जरूरतमंदों को दिया जाता अथवा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता, तो निश्चय ही आम लोगों का समर्थन-सहयोग प्राप्त कराने में सहायक होता। विशेषकर इसलिए क्योंकि आर्थिक मुद्दा पंजाब समस्या का एक अहम अंग है। बेरोजगार नौजवान आतंकवाद के घेरे में जितनी आसानी से आते हैं उतने कामकाजी नहीं।"

आज भी हमदर्द : बलवंत सिंह रामूवालिया

मरहम लगाने की जितनी जरूरत तब थी, उससे शायद कहीं ज्यादा आज है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ताजा पंजाब पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है इसे अधिकांश लोग नकार नहीं सकते। किंतु नये पैकेज के तीन मुद्दे चर्चा और विवाद का कारण बने। पहला, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के तहत पंचायत चुनाव जिसकी सरकार ने खूब डुगडुगी बजायी। दूसरी राजीव-लोंगोवाल समझौते के भविष्य पर असाधारण चुप्पी। तीसरा, सिख मनोविज्ञान से सीधे-सीधे जुड़ा १९८४ के दिल्ली दंगों के अपराधियों को सजा देने का मुद्दा।

मई से प्रारंभ होने वाले पंचायत चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग अवश्य करार दिया गया है, किंतु अधिकांश विपक्षी नेता इस कदम से असहमत हैं। गुजराल को अपने दौरे के दौरान यदि यह अहसास हुआ कि पंचायत चुनाव के घोषित समय 'टेंटेटिव' हैं और उसमें रद्दोबदल भी हो सकती है, तो कुछ अन्य विपक्षी नेता अंततः चुनाव कराये जाने पर ही शंका व्यक्त कर रहे हैं। जिनको विश्वास भी है कि चुनाव होंगे, उन्हें भी बढ़ती हिंसा के मौजूदा माहौल में उसके स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की उम्मीद नहीं। साथ ही, वे इस खतरे की ओर और संकेत करते हैं कि पंचायत चुनाव के बहाने आतंकवादी गिरोहबंद होकर उस पर अपना वर्चस्व न जमा लें और उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए पंचायतें खाद साबित न हों।

जनता दल सांसद यशवंत सिन्हा ने तो सीधे प्रश्न किया, "राष्ट्रपति शासन के दौरान पंचायत

चुनाव कराने का क्या तुक है, सिवाय इसके कि परंपराओं को तोड़ने का एक नया अध्याय शुरू हो? यदि मंशा लोकतंत्र की बहाली का ही है, तो विधान सभा चुनाव क्यों नहीं कराते? कांग्रेस हुक्मरानों का तरीका इतना टेढ़ा-मेढ़ा है कि वे एक जगह का एक रत्ती लाभ, दूसरी जगह तोले में भुनाने की कोशिश करते हैं।''

आगामी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रख कर पंचायत चुनावों को लोकतांत्रिक मुखौटा बनाने का आरोप कुछ हद तक सही है। किंतु इसके चलते यह कहना कि ये चुनाव होंगे ही नहीं, सही नहीं जान पड़ता। क्योंकि पंचायत चुनाव कराना सरकार की विवशता है। कारण, संविधान के ५९वें संशोधन के अंतर्गत पंजाब में राष्ट्रपति शासन मात्र एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र बहाली का बीजारोपण यदि अभी नहीं किया गया, तो अगले वर्ष हथेली पर बीज जमाना जैसा होगा। इस दिशा में सरकार की स्पष्ट नीति यह जान पड़ती है कि चाहे यह कदम कितना भी कीमती क्यों न साबित हो, किंतु इसको उठाना लाजिमी है। वैसे यह भी सच है कि पंचायत चुनाव यदि हो भी गये, तो लोकसभा चुनावों के पूर्व विधान सभा चुनाव होने की कतई संभावना नहीं।

जहां तक राजीव-लोंगोवाल समझौते का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की पूर्ण चुप्पी ने विपक्ष को पूर्णतया आश्चर्यचकित किया है। प्रख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह की टिप्पणी है, ''इसे कदाचित रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। कारण, इसके विभिन्न समयबद्ध मुद्दों पर आज तक अमल नहीं किया गया। न तो चंडीगढ़ का हस्तांतरण किया गया और न सतलज-यमुना नदी जल का बंटवारा। इसी प्रकार १९८४ के दिल्ली दंगों के अपराधियों को भी कठघरे में खड़ा नहीं किया गया।''

चालाकी: कदाचित सरकार को मालूम था कि जोधपुर बंदियों की रिहाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के दंगों को बनाया जायेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंजाब पैकेज के उल्लेख के साथ यकायक यह सूचना भी दी कि दिल्ली दंगों के संबंध में २३०० लोगों के खिलाफ कुल २२५ मुकदमे चलाये गये। इनमें ६ लोगों को आजीवन कारावास सहित कुल ८० लोगों को सजाएं दी गयी हैं, तो संसद ही नहीं समूचा देश भी हतप्रभ रह गया। कारण, इस कानूनी कार्रवाई की किसी को कानोकान खबर न थी। वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने इस संबंध में बातचीत करते हुए 'माया' से कहा, ''यदि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का मुकदमा खुली अदालत में चलाया गया, तो दिल्ली के हजारों निर्दोषों की हत्या का मुकदमा बंद कमरे में क्यों? जहां तक मेरी जानकारी है जो भी छुटपुट मुकदमे चले हैं वे लोगों ने निजी स्तर पर चलाये हैं। सरकार ने अपराधियों को कठघरे में खड़ा करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। दिल्ली के दंगों पर रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर अमल का सुझाव देने के लिए बनाई गयी जैन-बनर्जी समिति ने तो खुलेआम कुछ अपराधियों के नाम तक लिए थे—मसलन कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार। किंतु उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गयी।'' रामूवालिया ने जोड़ा, ''दिल्ली के दंगों के फसादियों को सजा की जगह खुली शह दी गयी है। कुछेक तो तख्तोताज पर विराजमान हैं।''

नब्ज पर हाथ: रिबेरो

यही अविश्वास पंजाब में केंद्र के प्रति भी बरकरार है। इसे दूर करने के प्रयास तो दरकिनार, विपक्ष को विश्वास में लेकर आम सहमति बनाने का भी किंचित प्रयास नहीं किया गया। बावजूद इसके की सर्वदलीय बैठक बुलाने संबंधी वक्तव्य समय-समय पर निरंतर जारी किये गये हैं। विपक्ष इसे शासक दल की बदनीयती का सबूत करार देता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में समूचे विपक्ष को 'खालिस्तान' समर्थक ठहरा कर उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, उससे विपक्ष को सरकार को आड़े हाथों लेने का मौका और मिल गया।

असमर्थ विपक्ष: विपक्षी नेताओं के साथ मिल-बैठ सहमति न करने के प्रश्न को सुनते ही केंद्र के एक वरिष्ठ मंत्री आगबबूला हो बोले, ''प्रश्न आम सहमति का नहीं, मात्र आलोचना करने का है। विपक्ष के इसी रवैये को भलीभांति समझते हुए हमने पहले पंजाब पैकेज प्रस्तुत करना अधिक उचित समझा। कारण कि इसके पहले बुलायी गयी बैठक में यही सब मुद्दे आलोचना के रूप में उठाये जाते। बीजारोपण से पहले जमीन तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। चूंकि पंजाब मसले के हल के लिए जमीन तैयार हो चुकी है, इसीलिए हम अगले कुछ सप्ताह में विपक्ष से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं।'' दिलचस्प बात यह है कि बाट राष्ट्रीय स्तर पर जोही जा रही थी और बातचीत राज्य स्तर पर आरंभ की जायेगी।

मौजूदा माहौल केंद्र को कठघरे में खड़ा करने की गर्मजोशी से परिपूर्ण है। किंतु यदि केंद्र सरकार मसले को हल करने में विफल रही है, तो विपक्षी दल भी अभी तक कोई ठोस, कारगर कार्यक्रम पेश नहीं कर पाये हैं। इसकी खिल्ली उड़ाते हुए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में अपने वक्तव्य के दौरान कहा, ''राष्ट्रीय मोर्चा पंजाब समस्या के हल को कितनी प्राथमिकता देता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि इसके लंबे-चौड़े ७१ सूत्री कार्यक्रम में पंजाब का मसला ६७वें नंबर पर है। अथक प्रयासों से तैयार किये गये इस कार्यक्रम में पंजाब हल संबंधी एकमात्र वाक्य है 'समाधान के लिए फौरी कदम उठाये जायेंगे।''

विडंबना यह है कि राष्ट्रीय स्तर के अलावा स्वयं पंजाब के राजनीतिज्ञों ने हिंसा की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी हैं। इसमें सर्वाधिक योगदान अकालियों का है। वे न तो अपना घर एक कर पाये हैं, न आतंकवादियों के खिलाफ मजबूत रुख ले सके हैं। न इस बात का स्पष्टीकरण कर पाये कि वे आखिर चाहते क्या हैं? रही-सही कसर कट्टरवादी धार्मिक नेताओं ने पूरी कर दी है।

आवश्यकता आज चौतरफा आचरण और दृष्टिकोण बदलने की है, जिसमें पुलिस, प्रशासन, राजनीतिज्ञ और यहां तक कि आम जनता की प्रमुख भूमिका आवश्यक है। समझौतापरक पैकेज प्रस्तुत करके सरकार ने सुलह-सफाई का हाथ बढ़ाया है। इस पृष्ठभूमि में विपक्ष के साथ होनेवाली बातचीत की महत्ता बढ़ जाती है। देखना यह है कि विपक्ष व सरकार की आगामी बातचीत किस मोड़ पर पहुंचती है और क्या दोनों एक न्यूनतम समान कार्यक्रम बना पाते हैं? मार्ग निष्कंटक होगा ऐसा सोचना भी महंगा साबित हो सकता है। कारण कि आज तक समाधान के लिए उठाये गये हर कदम का जवाब आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों में तेजी लाकर ही दिया है। सब कुछ दांव पर लगे होने के कारण 'खालिस्तान' से कम कोई भी सौदा उन्हें रास आने से रहा।

आतंकवादियों की इसी चिरपरिचित चाल को समझते हुए ही एक के बाद एक कदम उठाने की व्यवस्था की गयी है, जिसने कार्यवाही के बहुमुखी विकल्पों को खुला रखा है। स्वयं प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, ''हर कदम पर दृष्टि रखते हुए हम लगातार आकलन करेंगे। यदि हमें यह आभास हुआ कि स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है, तो हम गति धीमी कर देंगे। यदि स्थिति बिगड़ती दिखी, तो हम प्रक्रिया को रोकेंगे। यदि स्थिति बेहतर होती दिखी, तो हम गति तीव्र कर देंगे।'' शायद इसीलिए पर्यवेक्षकों का मानना है कि पंजाब आज एक बार फिर चौराहे पर खड़ा है। स्थिति चुनाव और राजनीति दोनों की परिधि से बाहर है। पंजाब में आज हरेक का एक ही नारा होना चाहिए 'शांति सर्वोपरि है, तत्पश्चात राजनीति।'

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

रश्मि
Rashmi
Rashmi
ZAFRANI PATTI
Rashmi
ZARDA
ZAFRANI PATTI
SCENTED CHEWING TOBACCO
SATYAPAL SHIVKUMAR
355, NAYA BANS, DELHI-110006 (INDIA)

पेश है जनाब एक स्वाद लाजवाब,

'रश्मि' ज़र्दे की विविधता में वही परम्परागत स्वाद,
वाह! क्या लाजबाब.......

रश्मि ज़र्दा

सत्यपाल शिवकुमार 355, नया बाँस, दिल्ली-110006

BLISS/DEL

(वैधानिक चेतावनी – तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।)

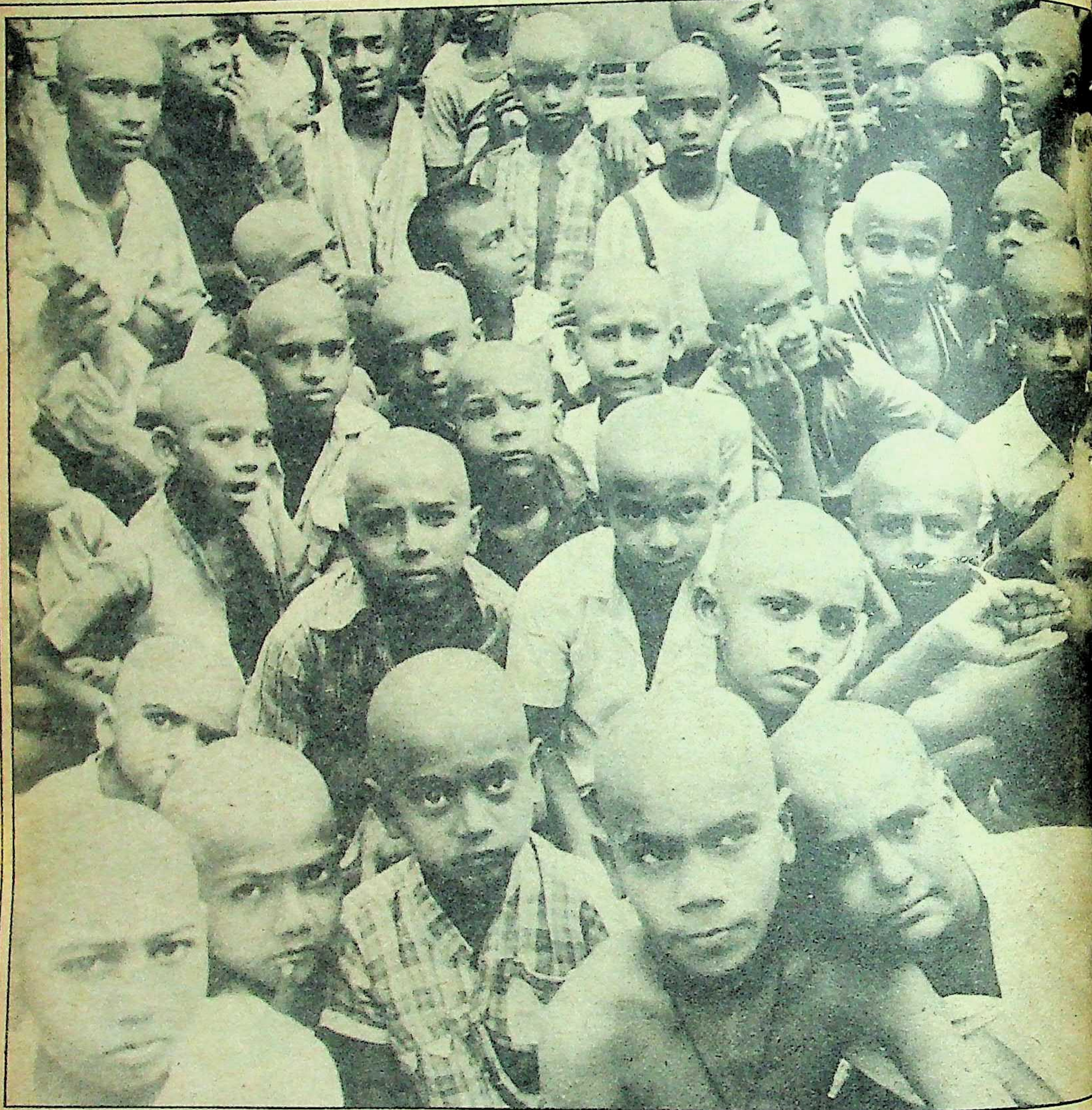

जो यतीम बन
गये ? : मृतकों के बच्चे

छाया: बल्लभ शाह

बड़ोदरा की त्रासदी

अवैध शराब के बेलगाम धंधे ने क्या कहर ढाया है ?

नशाबंदी के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी के राज्य गुजरात के बड़ोदरा शहर में पांच मार्च को जहरीली लट्ठा (देशी शराब) पीकर १३१ लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा तथा लगभग २०० लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। शराब से मरनेवालों में सबसे ज्यादा बड़ोदरा नगरमहापालिका के

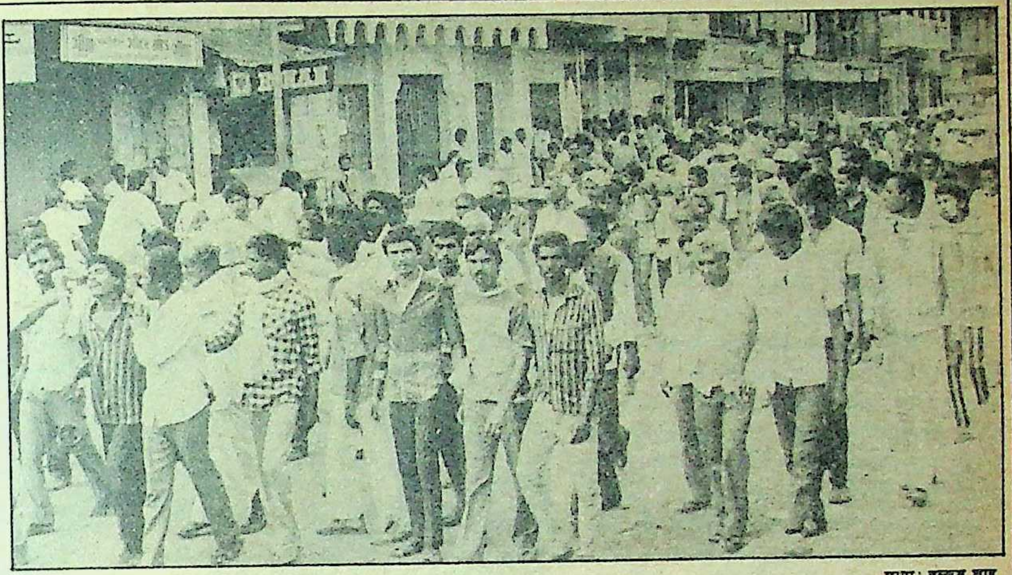

सामूहिक शवयात्रा

छाया : वल्लभ शाह

महात्मा गांधी के राज्य गुजरात के बड़ोदरा शहर में जहरीली शराब पीकर १३१ लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा तथा लगभग २०० लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।

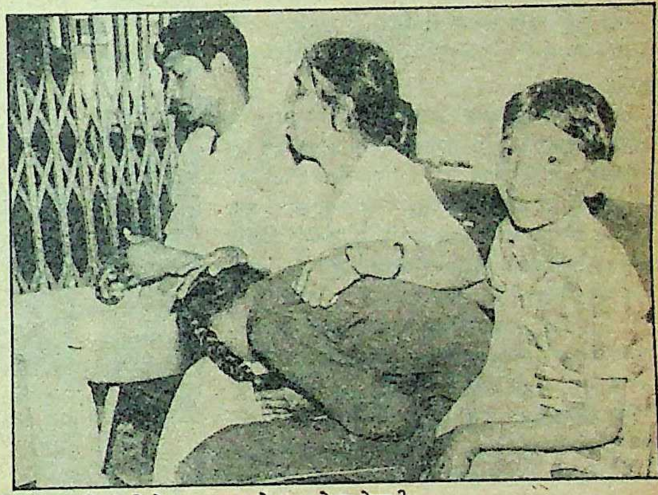

जनता मरे या जिये, प्रशासन को क्या लेना-देना ?

रंगे हाथों [illegible] बेचनेवाली महिला

छाया : [illegible]

सफाई कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों एवं अन्य मृतकों में अधिकांश हरिजनवास, रणवास, गजरावाड़ी, किशनवाड़ी, पाथेर गेट तथा वरानियां इलाकों की झुग्गीझोंपड़ियों के निवासी एवं निम्न मध्यवर्गीय लोग हैं। ये सभी इलाकें शहर के वाड़ी पुलिस-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वरनपुरा में बनी इस शराब के विक्रेताओं-अरविंद जायसवाल, चिमन जायसवाल तथा लोकेश जायसवाल—को पुलिस हिरासत में ले चुकी है।

इस हादसे की करुणा का अंदाज बड़ोदरा के सर जयाजी जनरल अस्पताल में आज भी देखने को मिलता है, जहां गरीब परिवारों के बच्चे और विधवाएं अपने पिता अथवा पति के नेत्रहीन हो जाने से भविष्य के अंधकार को देख रोते-बिलखते नजर आते हैं। अस्पताल में चारों ओर जिस दिन हादसा हुआ था, उस दिन तो अस्पताल में बड़ा मर्मांतक दृश्य था। चारों ओर पीड़ितों की चीख-पुकार मची हुई थी, इनमें अस्पताल में शैया की कमी के कारण कुछ मरीजों का इलाज जमीन पर ही किया जा रहा था। अस्पताल का शवगृह भर गया था, अतः लाशें परिसर में खुले आसमान के नीचे ही रखी जा रही थीं। शव परीक्षण कक्ष में भी स्थान की कमी के कारण शव परीक्षण खुले में चल रहे थे। इतना ही नहीं, शवदाह गृह में भी स्थान न होने के कारण एक परिवार के कई मृतकों की अंत्येष्टि एक ही चिता पर की जा रही थी।

इस दुखद घटना के बाद बड़ोदरा पुलिस के आयुक्त पीके बंसल सहित वाड़ी के अनेक पुलिस निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों एवं हेड कांस्टेबलों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है तथा गुजरात के मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी ने उक्त हादसे की उच्चस्तरीय जांच की घोषणा की है। **—विशेष प्रतिनिधि**

प्रकाश पादुकोन

संन्यास लेने की मजबूरी

बैडमिंटन के विश्वविजेता प्रकाश पादुकोन को अंततः खेल से संन्यास क्यों लेना पड़ा ?

किसी खेल का विश्वविजेता होना स्वयं में एक महान उपलब्धि है। फिर प्रकाश पादुकोन ने तो भारतीय बैडमिंटन के एक शानदार युग का प्रतिनिधित्व किया है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि भारत ने बिलियर्ड के क्षेत्र में विलियम जोन्स, माइकल फरेरा तथा ओबी अग्रवाल जैसे अनेक विश्वविजेता पैदा किये, किंतु इनमें से कोई भी अपने क्षेत्र में वह प्रभाव नहीं छोड़ सका, जो प्रकाश ने अपने क्षेत्र में छोड़ा है। इसी तथ्य में प्रकाश की महानता निहित है।

लोगों का ऐसा मानना है कि विजेता आंकड़ों से परे होते है तथा आंकड़े मुसीबतों पर सफलता पाने के लिए उनके द्वारा किये गये कठिन परिश्रम, लिए गये दृढ़-संकल्प तथा त्याग की कहानी नहीं बताते। यह मान्यता प्रकाश की सफलता से संबंधित आंकड़ों पर भी पूरी तरह लागू होती है। प्रकाश १९८०-८१ के दौरान विश्व बैडमिंटन के शीर्ष-स्थान पर थे। उनकी पृष्ठभूमि, उनकी प्रारंभिक कठिनाइयां तथा अपने लिए निर्धारित बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनके अनन्य समर्पण की जानकारी के अभाव में उनकी सफलता की महत्ता को समझ पाना कठिन होगा।

अच्छी शुरुआत : उल्लेखनीय है कि प्रकाश ने अपने जीवन की प्रथम प्रतिस्पर्धा में मात्र छह वर्ष की आयु में भाग लिया था। इससे वे प्रारंभिक दौर में ही बाहर भी हो गये थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। प्रकाश को प्रकाश बनाने में उनकी अपनी मेहनत तथा लगन के अतिरिक्त उनके पिता रमेश का भी योगदान कम नहीं है।

प्रकाश के अतिरिक्त रमेश के तीन और पुत्र तथा एक पुत्री है। इनमें प्रदीप सबसे बड़ा है। अन्य दो के नाम महेश तथा हरीश हैं। इन चारों में से महेश को छोड़कर अन्य सभी ने बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रदीप तथा प्रकाश ने बहुत बढ़िया युगल बनाया तथा जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय उपाधि जीती।

यदि प्रकाश पादुकोन के शुरू के दौर पर नजर डाली जाये, तो पता चलेगा कि प्रकाश को प्रारंभिक जीवन में बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। मालेस्वरम (बंगलौर) स्थित उनके घर के निकट बना कैनरा यूनियन क्लब का सीमेंट कोर्ट बहुत साधारण था, जहां उनके पिता दीवार पर घंटों चिड़िया से चोट करवा कर उनकी रफ्तार बनवाने का अभ्यास करवाते थे। अपने उन दिनों को याद करते हुए प्रकाश कहते हैं, "तब बहुत कम सुविधाएं थीं तथा कैनरा यूनियन क्लब तथा मालेस्वरम यूनियन क्लब के सीमेंट कोर्ट अत्यंत साधारण थे।"

प्रकाश जब जूनियर खिलाड़ी थे तभी जानकार लोगों ने उनके प्रर्दशन को देखकर एक नये सितारे के जन्म की घोषणा कर दी थी। १९७१ में मद्रास में हुए राष्ट्रीय खेलों ने प्रकाश के युग के प्रारंभ की घोषणा कर दी। इस वर्ष प्रकाश ने घुटने ठीक न होने के बावजूद पुरुषों का जूनियर तथा सीनियर एकल खिताब जीता था। "वास्तव में मुझे

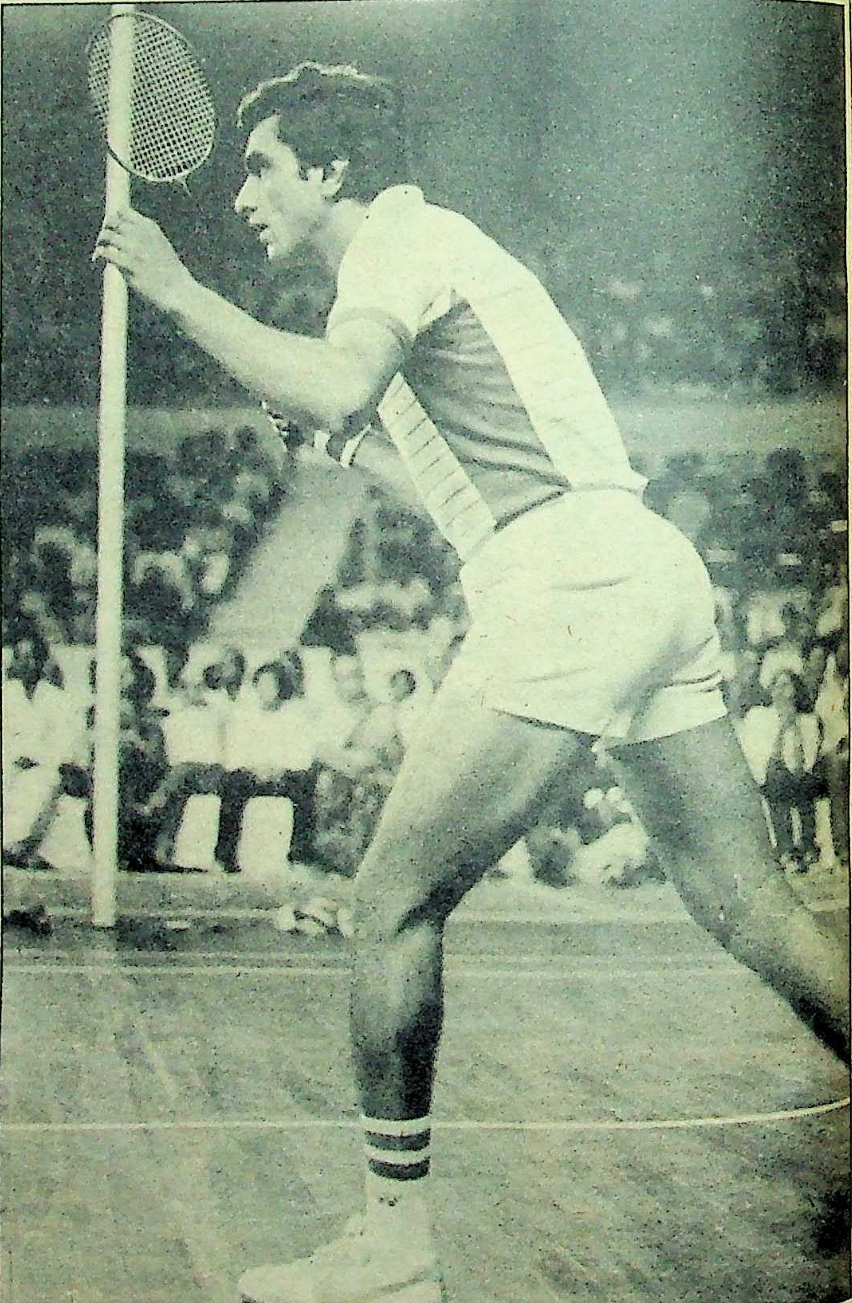
भारतीय बैडमिंटन के एक अध्याय : प्रकाश पादुकोन

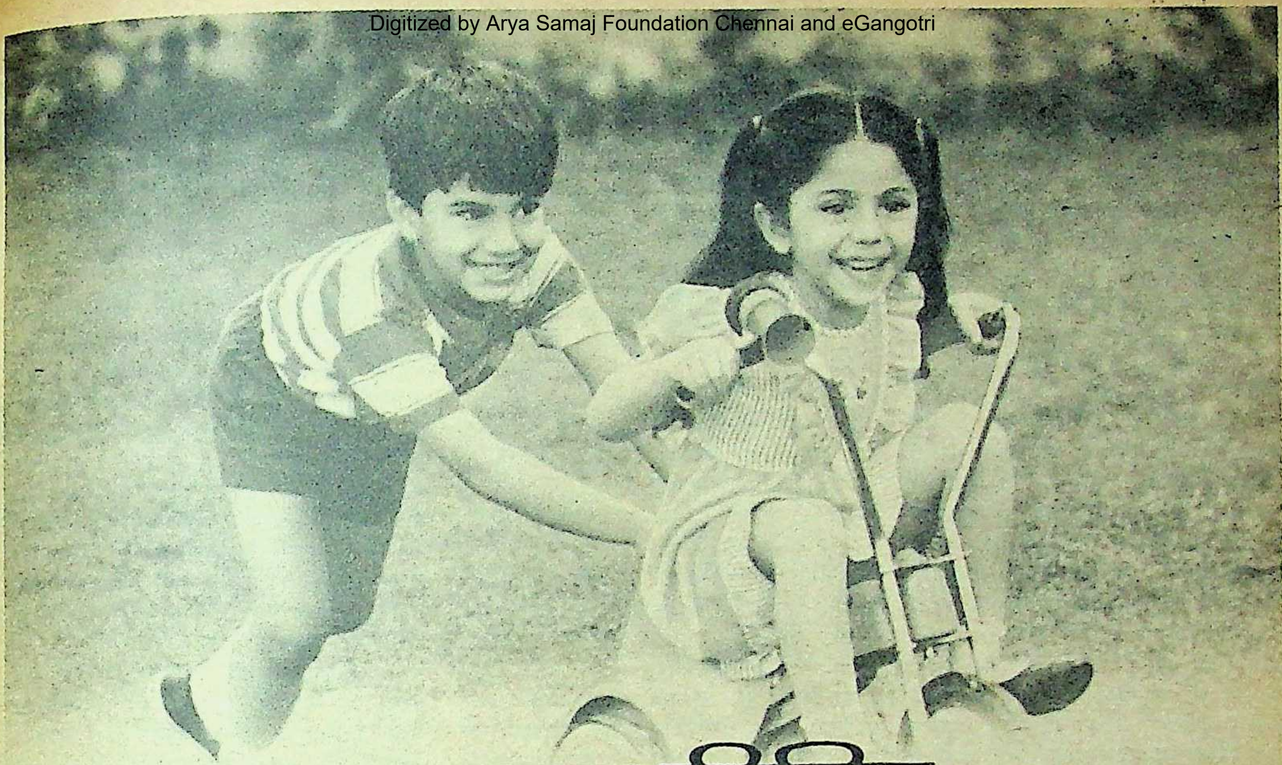

कल्पना कीजिए,
ये दस साल बाद कैसे होंगे !

आपके प्यारे-दुलारे बच्चे स्वास्थ्य की जीती-जागती तस्वीर होंगे, जिन्हें देख आपको गर्व होगा। मां होने के नाते आप उनका जीवन बनाने के लिए सब कुछ जो कर रही हैं।

और आपकी प्यार-भरी देखभाल में उन्हें उचित पौष्टिकता देना भी शामिल है।

हॉर्लिक्स की पौष्टिकता। आपके बढ़ते बच्चों के लिए।

''हॉर्लिक्स में अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्त्व—प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज पदार्थ—होते हैं।

और साथ में, मज़बूत दांतों और स्वस्थ हड्डियों के लिए अधिक कैलिशयम भी।

यही है हॉर्लिक्स की पौष्टिकता जिससे आपका बढ़ता बच्चा चुस्त और तन्दुरूस्त रहता है।''

PROTEINS ✓
VITAMINS ✓
MINERALS ✓
CARBOHYDRATES ✓
CALCIUM ENRICHED ✓
EASY TO DIGEST ✓
ENERGY SOURCE ✓
COMPLETELY NATURAL ✓
Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
The Great Nourisher

पौष्टिकता से भरपूर

HTA 6223 HIN

राष्ट्रीय एकल उपाधि पुनः प्राप्त करने का उनका प्रयास तब ध्वस्त हो गया जब जम्मू में वे एक बहरे और गूंगे खिलाड़ी से हार गये।

डाक्टरों ने सलाह दी थी कि मैं वह राष्ट्रीय खेल छोड़ दूं।" प्रकाश बताते हैं, "क्योंकि उन्हें आशंका थी कि खेलने से मेरे घुटने की चोट बढ़ जायेगी। लेकिन मैंने अवसर को गंवाना उचित नही समझा तथा चारों प्रतियोगिताओं में नाम दर्ज करवा लिया। मैं नही जानता कि मैं प्रतियोगिताओं की कठिन शृंखला को कैसे पार कर गया?"

इसके बाद से प्रकाश का बैडमिंटन संबंधी सौभाग्य अनवरत चढ़ता, चमकता गया। १९७१ में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने प्रकाश पर दूरगामी प्रभाव डाला। प्रकाश के आदर्श बैडमिंटन खिलाड़ी तथा इंडोनेशिया के महान विश्व चैंपियन रूडी हार्टोनो प्रदर्शन मैचों की एक शृंखला खेलने भारत आये। इस महान खिलाड़ी के खेल का अवलोकन करने का सौभाग्य प्रकाश को जयपुर में मिला। इस घटना को याद करते हुए प्रकाश बताते हैं, "मैंने हार्टोनो को मैच से ठीक पहले 'फिटनेस' क्रिया के दौरान देखा। हालांकि वे 'फिटनेस' क्रिया के दौरान एकदम अकेले रहते थे तथा उन्हें यह पसंद भी नहीं था कि कोई उन्हें देखें, किंतु मैंने इसकी व्यवस्था कर ली थी। सच तो यह है कि उनके दुरुस्ती क्रम (फिटनेस रुटीन) को देखकर ही मैंने शारीरिक दुरुस्ती का महत्व समझा। रूडी को देखने के बाद ही मैंने अपना दृष्टिकोण बदलने का निश्चय किया तथा शारीरिक अनुकूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।"

हालांकि प्रकाश के जीवन का परिवर्तन-स्थल फिलहाल कई वर्ष दूर था, किंतु इस बीच प्रकाश देश में सर्वोच्च खिलाड़ी बने रहे। इस दौरान उन्हें एक आकस्मिक हार का सामना जरूर करना पड़ा, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय पुरुष एकल उपाधि लगातार नौ वर्षों तक जीतने से कोई रोक नहीं सका। देश में उनकी सी कुशलता तथा तकनीक वाला दूसरा कोई बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं था।

राष्ट्रीय विजेता बने: वर्ष १९७६ प्रकाश के जीवन में एक नये अध्याय की शुरुआत था। इस वर्ष स्वर्गीय सैयद मोदी के साथ उन्हें छह सप्ताह के गहन-प्रशिक्षण हेतु इंडोनेशिया भेजा गया था। जकार्ता (इंडोनेशिया) में उन्होंने प्रशिक्षण का इंडोनेशियाई तरीका सीखा और इससे काफी लाभान्वित हुए। उसी वर्ष उन्होंने हैदराबाद में आयोजित एशियाड बैडमिंटन संघ चैंपियनशिप में भारत को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया। यद्यपि प्रकाश ने अपने दोनों एकल जीत लिए, किंतु भारत जापान से हार गया। उन्होंने केन्जी जेनिया को प्रारंभिक एकलों के सीधे खेलों में हराया तथा मसाओ मुचिदा के विरुद्ध मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। पहले खेल में ७-१४ से पिछड़ कर प्रकाश खेल समाप्ति से एक प्वाइंट पहले ११-१४ पर पहुंच गये। अगले दो खेलों में प्रकाश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। उन्होंने मुचिदा को १५-०, १५-० से पीट दिया। इस पराजय से मुचिदा इतना अपमानित हो गये कि मैच की समाप्ति के शीघ्र बाद उन्होंने अपना रैकट तोड़ डाला था। इसी के साथ प्रकाश राष्ट्रीय विजेता बने।

इसके बाद प्रकाश ने विश्व-विजय का अभियान प्रारंभ किया। एडमांटन, कनाडा में आयोजित कामन वेल्थ स्वर्ण को उन्होंने १९७८ में इंग्लैंड की शक्ति को धूल-धूसरित करके जीता। १९७९ में उन्होंने तत्कालीन विश्वविजेता डेनमार्क के फ्लेमिंग डेफ्स को हराकर 'इवनिंग आफ चैंपियंस टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने 'लंदन मास्टर्स' नामक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। इसके बाद उनकी १९८० की 'जादुई विजय-यात्रा' प्रारंभ हुई। इस वर्ष उन्होंने डेनिश ओपन, स्वीडिश ओपन तथा आल-इंग्लैंड उपाधियां एक पखवाड़े में जीत कर बिना ताज का विश्वविजेता होने का गौरव प्राप्त किया। अपनी इस विजय-यात्रा के दौरान उन्होंने रूडी हार्टोनो सहित तत्कालीन सभी बड़े खिलाड़ियों को कोर्ट में धूल चटाई। अंततोगत्वा, प्रकाश भारत के विश्वविजेता खिलाड़ी हो गये।

प्रकाश की यह विजय-यात्रा अपेक्षाकृत विलंब से प्रारंभ हुई। वे अपने खेल जीवन के शिखर चरम पर तब पहुंचे जब उनकी युवावस्था अंतिम पड़ाव पर थी। क्योंकि जब उन्होंने लंदन स्थित विम्बले में अखिल-इंग्लैंड प्रतिस्पर्धा जीतनेवाला एकमात्र भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया था, उस समय उनकी अवस्था २५ वर्ष थी।आज की इस प्रतिस्पर्धा की गणना अनधिकृत विश्व चैंपियनशिप के रूप में होती है। इस संबंध में स्वयं प्रकाश का कहना है, "मैंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरुष खिताब १९७१ में जीता तथा अगले वर्ष प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया, जब मुझे न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेलने के लिये थामस कप टीम में शामिल किया गया। १९७३ में जब मैं १८ वर्ष का था, मैंने पहली बार अखिल-इंग्लैंड टूर्नामेंट में भाग लिया। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से अगले तीन वर्षों तक मुझे अनेक कारणों से बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया गया। मुझे पैसे की कमी के कारण बाहर नहीं भेजा गया। अतः मुझे सफलता पाने में देर हुई।"

शादी की परिणति: कोर्ट से बाहर अविवाहित प्रकाश बंबई की 'महिंद्रा एण्ड महिंद्रा' के एक कार्यपालक की उजाला कारकल नामक पुत्री के संपर्क में आये तथा जल्द ही परिणय-सूत्र में बंध गये। इसके साथ ही प्रकाश के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसका संबंध उनके क्रमिक ह्रास से है।

यह वह समय था, जब चीनियों ने १९८१ में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ में पुनः सम्मिलित होने का निश्चय किया था। चीनियों के पुनर्प्रवेश ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन पर यथेष्ट प्रभाव डाला था। चीनियों की सपाट पलट वाले तेज परिवर्तनों की शैली ने सारे अंतरराष्ट्रीय पैमाने में सुधार आवश्यक बना दिया था।

चीनियों के प्रवेश से विश्व बैडमिंटन परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। जाहिर है, उनके स्मैशों का सामना करने के लिए नये अभ्यास और कला की जरूरत थी। चीनियों के प्रवेश ने ही प्रकाश की शक्तिशाली स्मैश के अभाव की कमी को उजागर कर दिया। इसी कमी को पूरा करने तथा चीनियों से निबटने के लिये प्रकाश ने टास तथा ड्राप शैली का प्रयोग किया, जिससे चीनी स्मैश का अवसर न पा सकें। इस तरह प्रकाश ने प्रत्येक बड़े चीनी खिलाड़ी को हराना जारी रखा। किंतु इतने वर्षों के अनवरत कठिन परिश्रम ने पुरानी चोटों को पुनः उभार दिया था।

नतीजतन समय तथा उम्र के साथ-साथ प्रकाश का खेल भी ढलता गया। व्यावसायिक जीवन के लिए शत प्रतिशत दुरुस्त होना आवश्यक होता है। और शत प्रतिशत दुरुस्ती लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती। अतः यह जरूरी था कि प्रकाश का अंतरराष्ट्रीय दर्जा कम हो जाता।

संन्यास की तैयारी: १९८१ में आल-इंग्लैंड उपाधि हार जाने के बाद भी वे अंतरराष्ट्रीय बैठमिंटन में एक शक्ति बने रहे। १९८२ में हांगकांग में क्लेरियन कप की विजय उनकी अंतिम अंतरराष्ट्रीय सफलता थी। बाद में फ्रास्ट ने उनकी विश्व नंबर की स्थिति को समाप्त कर दिया।

१९८६ के दिसंबर में भारत लौटने के बाद उन्होंने देश में खेल की खराब दशा तथा यहां की घटिया किस्म की चिड़ियों के खिलाफ आवाज उठायी। राष्ट्रीय एकल उपाधि पुनः प्राप्त करने का उनका प्रयास उस समय ध्वस्त हो गया, जब वे जम्मू में राजीव बग्गा नामक एक बहरे तथा गूंगे खिलाड़ी से हार गये। जमशेदपुर राष्ट्रीय खेलों में सुशांत बोरा से हार जाने के बाद तो उन्होंने खेल से संन्यास लेने का निश्चय कर लिया।

कुछ भी हो, भारतीय बैडमिंटन के प्रति प्रकाश का दृष्टिकोण आज भी आशावादी है। उनके अनुसार देश में अनेक प्रतिभासंपन्न जूनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन आवश्यकता है, सुविधाएं बढ़ाने की। "हमारे यहां की सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों से बहुत कम हैं।" प्रकाश का कहना है, 'मैंने पर्याप्त खेला है तथा अब मैं नये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना पसंद करूंगा।"

इस तरह भारतीय बैडमिंटन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की समाप्ति हुई। शायद प्रकाश को इस बात का दुख हो कि वे यश के समय संन्यास नहीं ले सके। किंतु सच यह है कि प्रकाश ने अपने को खेल में अमर बना देने के लिए बहुत कुछ किया है।

—'माया' खेल संवाददाता

शैतानी हरकत

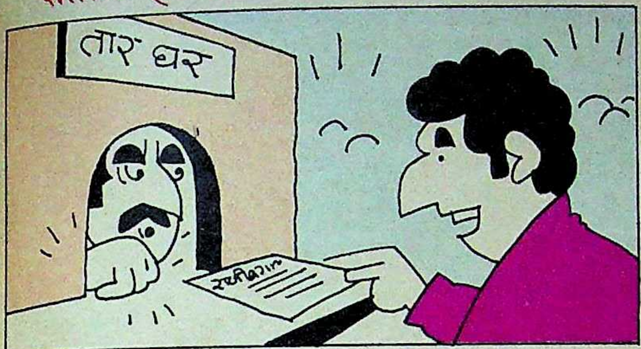

कुछ ऐसे सनकी और सिरफिरे होते हैं कि वे कब क्या कर दें, खुद नहीं जानते। कुछ साल पहले ३१ मार्च, १९८५ को देवरिया जिले के हाटा निवासी बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र लालमोहन राम ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित २५२ फुट ऊंचे विश्वनाथ मंदिर की मुंडेर पर चढ़कर यह ऐलान कर दिया था कि यदि राजीव गांधी जातिवाद के हिमायती नहीं हैं, तो वे अपने लड़के की शादी मेरी भतीजी से और अपनी पुत्री की शादी मेरे छोटे भाई से कर दें, वरना मैं जान दे दूंगा। इस दुराग्रह से बनारस का पूरा शासन-शटक सकते में आ गया था। दस घंटे के निरंतर प्रयास के बाद उस 'समाज सुधारक' पर काबू पाया जा सका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह ऐसा इकलौता सिड़ी था। हाल में मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक चौपायों के चिकित्सक ने कुछ ऐसी ही नागवार हरकत की है।

हुआ यह कि बालाघाट के विनोद नाम के एक २८ वर्षीय सिड़ी पशु चिकित्सक के मन में माननीय प्रधानमंत्री की सुपुत्री से शादी करने की एक शैतानी इच्छा जागृत हो गयी, सो वे सीधे तारघर पहुंच गया अपना फितूर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तारघर के कर्मचारियों की मुस्तैदी ही थी कि उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। बहरहाल, पुलिस ने उस जानवरों के डाक्टर को पागल ऐक्ट के तहत बंद कर दिया है।

चूहे बनाम पत्नी

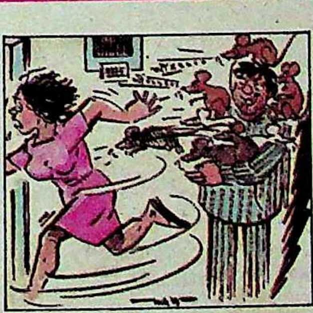

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जानवरों से वे ही लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। लेकिन यदि कोई पत्नी अपने पति पर दिलोजान से न्यौछावर हो, और पतिदेव चूहे-बिल्लियों से दिल लगा बैठें, तो उस पत्नी के पास घर छोड़कर जाने के सिवाय और क्या रास्ता होगा? लंदन की श्रीमती रोज के साथ कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। दरअसल, श्रीमती रोज के ४५ वर्षीय पति केन चूहों के इतने प्रेमी हैं कि उन्होंने घर में तकरीबन दो सौ चूहे पाल लिये। जब श्रीमती रोज से अपनी उपेक्षा नहीं सही गयी और वे रोज-रोज की चख-चख से परेशान हो गयी, तो उन्होंने एक दिन अपने पति को धमकी दे डाली, "इस घर में या तो ये दो सौ चूहे रहेंगे, या मैं? तुम हम दोनों में से एक का चुनाव कर लो।" केन ने चूहों के साथ रहना ही बेहतर समझा। अपने पति के इस कटु व्यवहार से दुखी होकर बेचारी रोज ने अपने २५ वर्षीय दाम्पत्य जीवन को तिलांजलि दे दी। श्रीमती रोज ने रोते हुए यह भी कहा, "मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका पशु-प्रेम चूहों को प्यार करने तक की सीमा तक पहुंच जायेगा।"

थूको अभियान

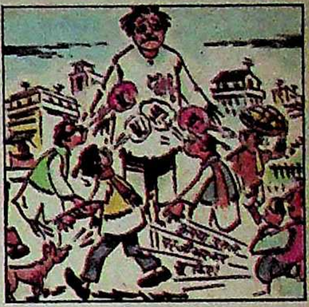

हिंदुस्तान में छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े स्तर पर खरीद-फरोख्त की राजनीति चालू है। कोई विधायकों को खरीदकर लाबिंग कर मुख्यमंत्री की कुरसी हथियाता है, तो कोई सांसदों को प्रलोभन देकर प्रधानमंत्री होने का सपना संजोये रहता है। और यह रोग हमारी राजनीति में ऊपर से नीचे तक घुन की तरह ऐसा लग गया है कि पिछले दिनों कानपुर में जो महापौर का चुनाव हुआ, उसमें भी सभासदों ने अपनी कीमतें लगायीं। लेकिन लगता है जनता को यह बेच-खरीद की राजनीति समझ में आ गयी है। ऐसे ही सभासदों को तिरस्कृत करने के लिए जनता ने वहां एक अनूठा-अभियान चलाया।

हुआ यों कि एक तरफ महापालिका प्रांगण में नवनिर्वाचित महापौर और सभासदों का शपथ-ग्रहण समारोह हो रहा था, तो दूसरी ओर पब्लिक ने बेईमान सभासदों का विरोध करने के लिए फूलबाग के निकट प्रतीक रूप में एक सभासद का आदमकद पुतला बनाकर खड़ा कर दिया और आयोजक हाथ में माइक लेकर राहगीरों से उस पर थूकने की अपील करने लगे। उधर से गुजरनेवालों ने उस पर जी भर कर थूका। थूको-अभियान के बाद भीड़ ने जब सभा का रूप ले लिया, तब वहां भाषणबाजी भी शुरू हो गयी और भारी धन लेकर महापौर के चुनाव में अपना वोट बेच देने के लिए सभासदों की भर्त्सना की गयी। बाकायदा इस अभियान में नगर की दो सौ से अधिक संस्थाओं, जिनमें बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों की भी संस्थाएं शामिल रहीं, ने शिरकत की।

खुशनसीब शेरी

शेरी बहुत खुशनसीब है। उसके दादा ही नहीं, दादा के दादा भी मौजूद हैं—और मौजूद ही नहीं, १०७ वर्ष की उम्र के बावजूद अपने बलबूते सीढ़ियां चढ़ते हैं और ६० पंक्तियों की कविता को बिना हांफे सस्वर पढ़ लेते हैं। इन बुजुर्गवार का नाम है हीरा सिंह और रहते हैं दिल्ली की शाहदरा बस्ती में। इन्हीं हीरा सिंह के पौत्र का पौत्र है, शेरी। लेकिन तीन माह के शेरी के लिए आगे चल कर एक परेशानी पैदा होगी। वह यह है कि वह अपने दादा के दादा को क्या कह कर पुकारेगा? दरअसल शेरी के २७ वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट पिता देविंदर पाल सिंह अपने बाबा को बाबाजी और बाबा के पिताजी को बड़े बाबाजी कह कर पुकारते हैं। अब शेरी या तो बड़े-से-बड़े बाबाजी कह कर पुकारे या फिर उसे बाबा नं० वन बाबा नं० टू जैसे संबोधनों का सहारा लेना पड़ेगा।

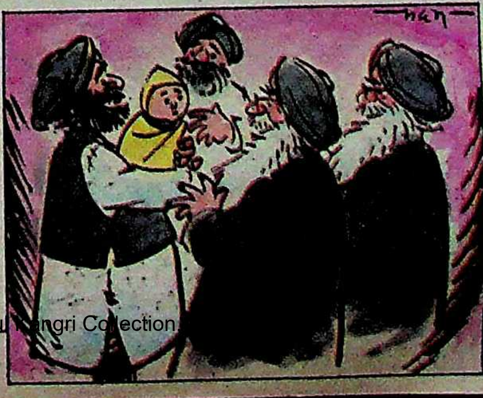

—संयोजन:
डा० मुश्ताक अली

औद्योगिक घरानों का महाभारत

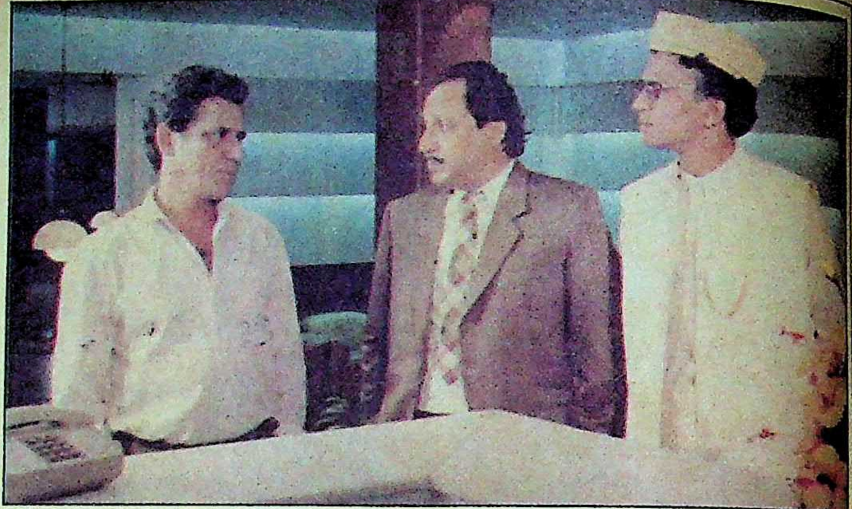

‘धर्मयुद्ध’ के एक दृश्य में: ओमपुरी, सुधीर पांडेय और अन्नू कपूर

जिस समय निर्माता-निर्देशक बीआर चोपड़ा ‘महाभारत’ तथा श्याम बेनेगल ‘भारत: एक खोज’ की शूटिंग फिल्म सिटी में कर रहे थे, उसी समय राहुल रवेल एक कलयुगी महाभारत ‘धर्मयुद्ध’ की शूटिंग कर रहे थे। ‘भारत: एक खोज’ में दुर्योधन की भूमिका निभाने के बाद ओमपुरी तुरंत ‘धर्मयुद्ध’ के सेट पर पहुंचे, जहां उन्हें ‘धर्मयुद्ध’ के कलियुगी दुर्योधन बीके के दुष्ट मित्र महावीर गुप्ता की भूमिका निभानी थी।

महाभारत की कथा को आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करनेवाला, ७०-७० मिनट के २६ एपीसोडोंवाला ‘धर्मयुद्ध’ भारत में बनने वाला प्रथम वीडियो सीरियल होगा, जिसे मंडी हाउस नियंत्रित सरकारी दूरदर्शन के बजाय दर्शक वीडियो पर अपने घरों में देख सकेंगे। ‘धर्मयुद्ध’ अपनी विवादास्पद कथावस्तु तथा व्यावसायिक सिनेमा की यूनिट व चित्रांकन के पहले ही सुर्खियों का विषय बनता जा रहा है। अगर मंडी हाउस ने इसकी लोकप्रियता से प्रभावित हो इसके प्रदर्शन की अनुमति दे दी, तो यह आधे-आधे घंटों के ७८ एपीसोडों में खतम होगा।

यों इसकी लोकप्रियता को देखते हुए केबिल टीवी संचालकों ने इसे केबिल टीवी चैनल पर रिलीज करने के लिए मुहमांगे आफर दिये हैं, लेकिन असली धर्मयुद्ध तो अब शुरू होनेवाला है—निर्माताओं, मंडी हाउस तथा केबिल टीवी संचालकों के बीच इसके टेलीकास्ट को लेकर, क्योंकि ‘धर्मयुद्ध’ के निर्देशक राहुल रवेल मंडी हाउस का चक्कर लगाने तथा आला अफसरों को खुश कर मनचाहा टाइमिंग एलाट और अधिक-से-अधिक एपीसोडों की संख्या बटोरने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हैं।

तीन पीढ़ियों का अन्तर्कलह: ‘धर्मयुद्ध’ एक बड़े औद्योगिक घराने में चलनेवाली अंदरूनी लड़ाई की तीन पीढ़ियों की कथा है, जिसके सभी पात्र महाभारत के पात्रों—शांतनु से लेकर कौरव-पांडव बंधुओं—सरीखे हैं। ‘भटनागर ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज’ का मालिक सर शांति भटनागर (नवीन निश्चल) अपनी पत्नी नलिनी (रामेश्वरी) के दो बार गर्भपात के बाद देवाशीष (आलोकनाथ) को जन्म देने के दौरान ही मृत हो जाने पर दुबारा शादी करता है जिससे उसकी दो संतानें केएन (अजीत वाच्छानी) तथा पीएन पैदा होती हैं। दोनों छोटे पुत्रों के लालन-पालन तथा उनके कैरियर के बारे में चिंतित बीमार पिता शांति भटनागर को देवाशीष इस बात का वचन देता है कि वह आजन्म अविवाहित रहकर दोनों (सौतेले) भाइयों की देखभाल करेगा। बड़े होने पर केएन एक पुत्र बीके (सुधीर पांडे) तथा पीएन पांच संतानों—धरम (शफी इनामदार), अधीन (अमजद खान), रघुवीर (पंकज कपूर) तथा पुत्रियों (सोनी एवं नम्रता) का पिता बनता है।

पीएन की हृदय गति रुक जाने के कारण हुई अचानक मौत के बाद भटनागर उद्योग के चेयरमैन का पद, जन्मत: नियमानुसार, धरम को मिलना था, लेकिन उसके नाबालिग होने के कारण कस्टोडियन की जिम्मेदारी उसके ताऊ केएन संभालते हैं, लेकिन अपने साले माथुर (अन्नू कपूर) के समझाने पर उनकी नीयत डोल जाती है और वे उद्योग समूह की बागडोर बालिग हो गये धरम को सौंपने के बजाय अपने बेटे बीके को सौंप देना चाहते हैं। अंतत: धरम और उसके भाइयों को अदालत की शरण लेनी पड़ती है।

अदालती लड़ाई फतह करने के विचार से बीके मामा माथुर की दुरभिसंधि से पीएन के औरस पुत्र महावीर गुप्ता (ओमपुरी) को इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल करा देता है कि पिता पीएन और मां द्वारा समाज के भय से अपनाने से इनकार कर देने के कारण वह पीएन की संतानों से बदला लेने के लिए किसी भी स्तर पर उतारू है। माथुर, बीके और महावीर की तिकड़ी साजिश कर निदेशक मंडल के एक और सदस्य रहमत अली की हत्या करा देता है। रहमत अली खान (होमी वाडिया) की पीए की संतानों के प्रति सहानुभूति ही उसकी मौत का कारण बनती है। अली के दादा सर शांति भटनागर के वफादार निजी सहायक तथा भटनागर खानदान के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, इसी एवज में देवाशीष ने रहमत अली खान को कंपनी का एक निदेशक बना दिया था।

मसालों से परहेज नहीं: नर्तकी के रूप में प्रेमानारायण

अली की हत्या खानदानी लड़ाई के शांत जल में जैसे तूफान बरपा कर देती है। अली की हत्या से क्षुब्ध रघुवीर उसकी मौत का बदला केएन तथा बीके से लेने पर उतारू हो जाता है। तो खानदान के भीतर आपसी झगड़े के खूनी लड़ाई का रूप ले लेने के खतरे को भांपकर देवाशीष कंपनी के ही एक और डायरेक्टर-एडवोकेट कृष्णा (राखी) से, जो यूनियन नेता भी हैं, मिलकर अदालती लड़ाई में पीएन के हक-वंचित पुत्रों की ओर से पैरवी करने का अनुरोध करते हैं, ताकि न्याय की रक्षा के साथ-साथ खूनी युद्ध होने से पूर्व ही रोका जा सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि न तो तब

महाभारत जैसा कलह : एक मीटिंग में शफी इनामदार, अमजद खान, पंकज कपूर और होमी वाडिया

'धर्मयुद्ध' के सेट पर निर्देशक राहुल रवेल, राखी और आलोकनाथ

'महाभारत' युद्ध की संभावना को भीष्म पितामह और कृष्ण रोक सके थे, न ही 'धर्मयुद्ध' में देवाशीष, कृष्णा का अलग-अलग और सामूहिक रूप से किया गया प्रयास।

आधुनिक रूपांतरण : 'धर्मयुद्ध' महाभारत का आधुनिक रूपांतरण है या आज औद्योगिक घरानों के भीतर चल रहे आपसी मुठभेड़, टकराव और अलगाव की कहानी ? 'शायद दोनों' कहनेवाले निर्देशक राहुल रवेल ने 'माया' को बतलाया, "यह एक बड़े औद्योगिक घराने के भीतर संपत्ति के बंटवारे तथा उस पर कब्जे को लेकर चलनेवाली कहानी है, जो सदियों से, परंपरा से चलती चली आ रही है—संयुक्त परिवार भाइयों-चचेरे भाइयों तथा उनके परिवारों के बीच चलती आ रही इन्हीं लड़ाइयों के कारण टूटते-बिखरते रहे हैं। अगर संपत्ति ज्यादा हो, तो वह सत्ता का रूप ले लेती है और सत्ता के लिए जंग स्वाभाविक ही है। 'धर्मयुद्ध' की कहानी भी एक ऐसे ही उद्योगपति घराने भटनागर खानदान की है, लेकिन शेयर, स्टाक एक्सचेंज का न तो यहां कोई संदर्भ है और न ही इसका 'महाभारत' से कोई लेना-देना है।"

राहुल रवेल भले ही 'धर्मयुद्ध' का संबंध 'महाभारत' से न मानें, लेकिन महाभारत के सभी पात्रों को उन्होंने न हूबहू लिया है। भीष्म की तरह देवाशीष भी आजन्म अविवाहित तथा मालिकाना हक से दूर रहने का प्रण लेता है। केएन (अजित वाच्छानी) का साला माथुर (अन्नू कपूर) शकुनि का प्रतीक है, तो बीके दुर्योधन का, धरम (शफी इनामदार) युधिष्ठिर, अधीन (अमजद खान) भीम तथा रघुवीर (पंकज कपूर) अर्जुन का और महावीर गुप्त (ओमपुरी) कर्ण का। राहुल रवेल ने कृष्ण को पुरुष के बजाय स्त्री कृष्णा (राखी) का रूप दिया है, जो भटनागर इंडस्ट्री की डायरेक्टर होने के साथ-साथ, मजदूर यूनियन की नेता भी है और वे वही भूमिका भी निभाती हैं इस खानदानी धर्मयुद्ध में जो कृष्ण ने निभायी थी।

होम इंटरटेनमेंट : राहुल रवेल 'धर्मयुद्ध' को फिल्मी मसालों से बचा नहीं सके हैं। "इस सीरियल में नाच-गाने तथा मार-पीट सभी कुछ है", राहुल बतलाते हैं, "लेकिन वे अयाचित या थोपे हुए नहीं हैं। आप इनकी जरूरत महसूस करेंगे इस सीरियल को देखकर, फिर दर्शक सिनेमा के बड़े या दूरदर्शन के छोटे परदे पर जो कुछ देखना चाहता है, उसमें मनोरंजन का पुट भी एक जरूरी तत्व है। मेरी कोशिश इस सीरियल में 'होम इंटरटेनमेंट' को एक नयी दिशा देने की रही है और वह मैंने दी है, इसीलिए इसमें नाच-गाने भी हैं।" और इन्हीं गानों में प्रेमा नारायण द्वारा एक नृत्य दृश्य में गवाया गया 'समधन नाचे है लहंगा उठा के चने के खेत में' गाना भी है, जिसके बारे में इसके संगीतकार अन्नू मलिक का कहना है—"इसमें अश्लीलता तो तब होती, जब इस दृश्य को (समधन वाले) आप पिक्चराइज करते। यह तो गांव-गांव में गाया जानेवाला लोकगीत है जिसे औरतें भिन्न-भिन्न अवसरों पर गाती हैं।"

'होम इंटरटेनमेंट' के पक्षधर राहुल का 'धर्मयुद्ध' एक तरह से होम डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन है। इसकी निर्मात्री हैं विभिन्न लोगों की पत्नियां—नीतू कपूर (ऋषि कपूर), रोहिणी आनंद (बिट्टू आनंद), हीथर नंदा (राजू नंदा) तथा रीता रवेल (राहुल रवेल)। 'महाभारत' के पटकथा संवाद लिखनेवाले डा० राही मासूम रजा ने 'धर्मयुद्ध' भी लिखी है। सलमा आगा तथा मुन्ना अजीज ने संगीतकार अन्नू मलिक की बनायी धुनों पर गाने तथा पंकज उधास ने गजल गाये हैं।

गरवारे प्लास्टिक्स ऐंड पोलियस्टर उद्योग समूह ने वीडियो कैसेट्स का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू कर निर्माण एवं वितरण का एक बहुत बड़ा तंत्र स्थापित किया है और उनका मानना है कि 'धर्मयुद्ध' की दर्शक संख्या का औसत दूरदर्शन पर प्रसारित होनेवाले अति लोकप्रिय सीरियलों के दर्शकों की संख्या से कम नहीं होगा, बल्कि इसमें फिल्मों की-सी 'रिपीट वैल्यू' होने के कारण इसे लोकप्रियता दूरदर्शन से अधिक मिलेगी। करोड़ों रु० की लागत से बन रहा 'धर्मयुद्ध' अगर २५ प्रतिशत दर्शकों की भी लोकप्रियता हासिल कर लेगा, तो ऊबाऊ स्तरहीन सीरियलों का प्रसारण केंद्र बन गये मंडी हाउस की इजारेदारी को भारी धक्का लगेगा, इसमें संदेह नहीं।

-रवींद्र श्रीवास्तव

छाया : एस बईसकर

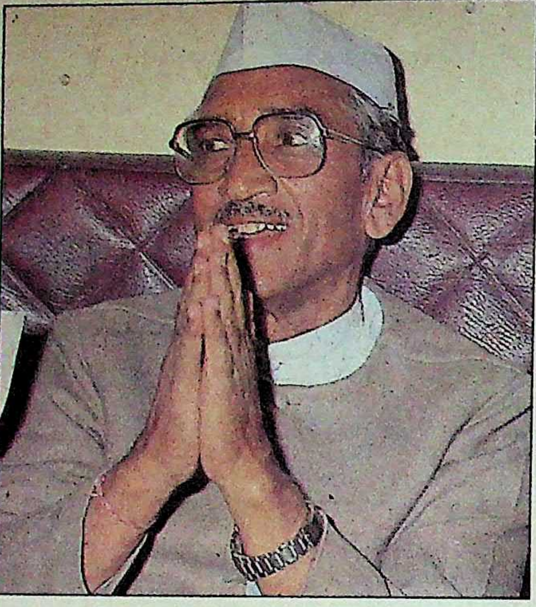

हेमवती नंदन बहुगुणा

अब उनकी बात बोलेगी

पहाड़ों की गोद में जन्मे थे वे। कदाचित राजनीति में शिखर छूने की महत्वाकांक्षा उन्हें इसी परिवेश ने दी थी। चोटी का रास्ता तलाशने में उन्हें घाटियों में भी भटकना पड़ा। लेकिन उनकी क्षमता हर किसी को यह अहसास कराती रहती थी कि वे किसी भी समय अंधी घाटी ने नमूदार होकर आरोहण करते दिखायी पड़ सकते हैं। अप्रत्याशित आरोहण की दक्षता और अनपेक्षित अवरोहण में धैर्य बनाये रखने की क्षमता के कारण ही नेहरू युग के बाद भारतीय राजनीति में कभी कोई बेखौफ यह नहीं कह पाया कि हेमवती नंदन बहुगुणा समाप्त हो गये। लेकिन राजनीति में 'फिनिक्स' की भांति पुनर्जीवित होने में सक्षम इस पर्वत पुत्र को १७ मार्च को अमरीकी डाक्टर पुनर्जीवित नहीं कर पाये।

२५ अप्रैल, १९१९ को गढ़वाल (उप्र) के छोटे से गांव बुगानी में एक पटवारी के परिवार में जन्मे हेमवती नंदन बहुगुणा उन नेताओं में से नहीं थे, जिनकी सियासत की अमरबेल विरासत के पेड़ पर फैली है। पिछले दिनों देवीलाल के हाथों अपमानित होने के कारण हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकदल-ब का अस्तित्व और बल दिखाने के लिए चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पर लखनऊ की विशाल रैली में ठीक ही कहा था कि लोग मेरी फसल काट ले गये हैं, लेकिन जमीन मेरे पास है। मैं और फसल उगा लूंगा। क्योंकि उन्होंने आजादी के संग्राम में भूमिगत नेताओं की भूमिका निभा कर और मजदूर संगठनों से जुड़ कर अपनी जमीन खुद बनायी थी और अपने संगठन कौशल तथा निपुण नेतृत्व के बल पर भारतीय राजनीति में देवदारु की तरह सिर और भुजा उठा कर वे ऊंचाई का प्रतिमान बने थे। देवदारु से उनकी तुलना इसलिए भी की जानी चाहिए, क्योंकि वह अपने अगल-बगल उगे पौधों को भी अपने साथ बढ़ने का मौका देता है, जबकि वट वृक्ष ऐसी उदारता से विरहित होता है। आज उत्तर-प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे अनेकानेक नेता हैं, जिनको पनपाने और पल्लवित करने का श्रेय हेमवती नंदन बहुगुणा को जाता है।

इलाहाबाद के हर गांव और हर कार्यकर्ता को नाम से जानने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा ने श्रमिक और विद्यार्थी आंदोलनों के जरिये अपना जनाधार तैयार करके १९५२ में विधानसभा में प्रवेश किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाने का मौका उन्हें १९६९ में उस समय मिला, जब कांग्रेस में विभाजन हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष को सुदृढ़ करने में अपनी चतुर रणनीति का परिचय दिया। संजीव रेड्डी के मुकाबले वीवी गिरि को जितवाने में उन्होंने जिन चाणक्यीय चालो का इस्तेमाल किया, उससे वे श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए एक राजनीतिक पूंजी बन गये। उनकी अप्रतिम संगठन क्षमता का पुरस्कार श्रीमती गांधी ने उन्हें कांग्रेस-इ का महासचिव बना कर दिया। इसके बाद बहुगुणा ने १९७५ तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। १९७३ में पीएसी के विद्रोह के बाद वे पं० कमलापति त्रिपाठी की जगह मुख्यमंत्री बने। यह उनके राजनीतिक जीवन के उत्कर्ष का काल था। लेकिन इसके बाद १९७५ में आपातकाल लागू हुआ और संजय गांधी के उदय के साथ बहुगुणा का पराभव शुरू हो गया। कांग्रेस में किसी नेता का जनप्रिय होना गुनाह है और मुख्यमंत्री के नाते बहुगुणा ने अपनी जनहितकारी योजनाओं तथा नीतियों को लागू करके यह गुनाह किया था। उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। नतीजतन उन्हें मुख्यमंत्री-पद छोड़ना पड़ा।

अपमान का हर हाल में बदला लेने वाले और राजनीति की भावी दिशा को भांप लेने में माहिर बहुगुणा को अपनी कला दिखाने का मौका उस समय मिला, जब १९७७ में श्रीमती गांधी और उनके राजपुत्र संजय गांधी के खिलाफ जनाक्रोश उमड़ा। बहुगुणा ने ३ फरवरी, १९७७ को कांग्रेस को तिलांजलि दे दी और बाबू जगजीवन राम के साथ 'कांग्रेस फार डेमोक्रेसी' को जन्म दे दिया। जनता पार्टी के शासनकाल में जो कुछ हुआ, वह जग जाहिर इतिहास है, लेकिन बहुगुणा ने शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती उस समय की, जब 'भांजे' संजय गांधी के अनुरोध पर वे २९ नवंबर, १९७९ को फिर से कांग्रेस में आ गये। इस घटना के समय बहुगुणा की विश्वसनीयता को जो धब्बा लगा, उसको वे ताउम्र नही धो पाये। यद्यपि बाद में उन्होंने कांग्रेस और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर गढ़वाल का ऐतिहासिक चुनाव जीता, लेकिन उनकी राजनीति पुनः गति नहीं पकड़ पायी। इधर स्वास्थ्य ने दगा देना शुरू कर ही दिया था। १९८३ में उन्हें दिल का इलाज करवाने अमरीका जाना पड़ा। फिर आये १९८४ के उन्मादी आम चुनाव और बहुगुणा अमिताभ बच्चन के हाथों अपने गढ़ इलाहाबाद में हार बैठे। यों उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद फटे लोकदल के एक धड़े के अध्यक्ष बन गये। हरियाणा में देवीलाल के नेतृत्व में उनकी पार्टी सत्ता में आयी, लेकिन बहुगुणा लोकदल-ब के नाम मात्र के अध्यक्ष रह गये थे। इसके बाद वीपी सिंह का उदय हुआ और इलाहाबाद लोकसभा में सिंह की विजय से शुरू हुआ विपक्षी एकता का प्रयास। वरिष्ठ विपक्षी राजनेता बहुगुणा को अपने से बेहद कनिष्ठ वीपी सिंह का नेतृत्व गवारा नहीं था और देवीलाल को यह गवारा नहीं था कि बहुगुणा वीपी सिंह के नेतृत्व को नकारें। इस खींचतान में देवीलाल ने उनके साथ जो व्यवहार किया, उसे स्वाभिमानी बहुगुणा कभी बरदाश्त करने वाले नहीं थे। नतीजतन उन्होंने अपने लोकदल-ब के अस्तित्व को विगलित नहीं होने दिया। २३ दिसंबर, १९८८ को उन्होंने राजनीति में पुनर्जीवित होने की अपनी क्षमता को लखनऊ में रैली आयोजित करके दिखाया, लेकिन उसके बाद सेहत ने उन्हें बहुत सक्रिय नहीं रहने दिया। एक मार्च को उन्हें इलाज के लिए अमरीका जाना पड़ा और फिर वहां से वे नहीं लौटे, उनका शव लौटा।

इलाहाबाद चुनाव हारने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने यह कह कर टोपी ओढ़ना छोड़ दिया था कि यह टोपी इलाहाबाद के लोगों ने उतारी है और वही जब तक नहीं रखेंगे, टोपी नहीं ओढ़ूंगा। जो पीडी टंडन पार्क कभी बहुगुणा के ओजस्वी भाषणों से अनुकंपित रहता था, उसी पीडी टंडन पार्क में जब बहुगुणा का शव रखा था, तो इस संवाद दाता के बगल में खड़े एक बुजुर्गवार ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, "हमें नहीं पता था कि बहुगुणाजी के सिर पर टोपी रखने के पहले उनके शव पर फूल चढ़ाने पड़ेंगे। हमको अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देते।" ऐसे कितने ही लोगों को पश्चाताप की आग में धधकता हुआ छोड़ कर हेमवती नंदन बहुगुणा का पार्थिव शरीर २० मार्च को चिताग्नि में विलीन हो गया। लेकिन बहुगुणा अब चाहे न बोलें, लेकिन उनकी बात बोलेगी। **—'माया' संवाददाता**

बजट ८९-९०

चुनावी वर्ष का हसीन धोखा

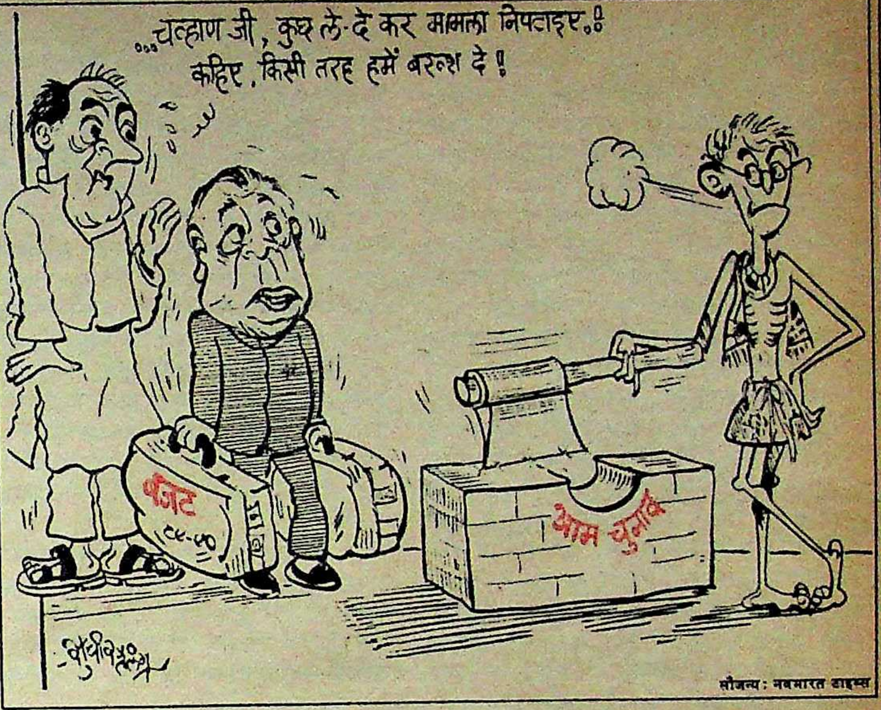
...चव्हाण जी, कुछ ले-दे कर मामला निपटाइए..!
कहिए, किसी तरह हमें बख्श दे!
बजट ८९-९०
आम चुनाव

सौजन्य : नवभारत टाइम्स

थोड़ी देर के लिए आप अपने को सरकार मान लीजिए। यह भी मान लीजिए कि चुनाव को मात्र दस महीने रह गये हैं और मतपेटियां आपको घूरने लगी हैं। आप भलीभांति वाकिफ हैं कि चार वर्ष पहले जब आपको सत्ता मिली थी तब और आज की परिस्थितियों में आकाश-पाताल का अंतर है। जनता आप से काफी नाराज है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी चरमरा गयी हो। तिजोरियां लगभग खाली हों और आर्थिक संकट देश पर मंडरा रहा हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप बड़ी चतुराई से जनता को मूर्ख बनाने के रास्ते हमवार करेंगे, ताकि आपकी सत्ता बनी रहे। जाहिर है, आप आर्थिक संकट से बाखबर होने के बावजूद चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करों में छूट देकर तो जनता को खुश नहीं कर सकते। न तो आप मनमाने ढंग से कर्ज ले सकते हैं और न ही अतिरिक्त नोट छापकर नर्म बजट पेश कर सकते हैं। आप मजबूर होंगे कि करों के रूप में धन एकत्र करें और देश की जरूरतों को पूरा करें। किंतु यदि आप चालाक हैं, तो करों का बोझ लादकर भी कुछ ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे देश के आर्थिक संकट का मुखौटा भी जनता के सामने पेश न हो और मामूली प्रलोभनों के सहारे धोखा देकर जनता का मत भी प्राप्त हो जाये।

नयी धुन की जरूरत : ऐसे में आपके समक्ष सिवाय इसके और क्या रास्ता होगा कि आप एक नयी धुन की रचना करें। क्योंकि आप पर यह जाहिर हो चुका है कि 'गरीबी हटाओ' की आपकी पुरानी धुन अब बेअसर हो चली है। कारण सिर्फ यह है कि इस धुन के सहारे आप और आपके पूर्वज काफी दिन तक सत्ता में बने रहे हैं, किंतु 'गरीबी' का खातमा नहीं हुआ। यही नहीं, अब तो जनता 'गरीबी हटाओ' की धुन से बोर भी होने लगी है। जनता यह समझ गयी है कि आप यह धुन गरीबों को फुसलाकर वोट प्राप्त करने के लिए बजाते हैं, जबकि वास्तव में आप मदद अमीरों की करते हैं। ऐसे में नयी धुन की रचना का महत्व अपने आप उजागर हो उठेगा तथा आप के मन में बैठा चालाक राजनीतिक आपको नयी धुन की रचना के लिए मजबूर कर देगा। नतीजतन आप एक नयी धुन बनायेंगे। यानी 'गरीबी हटाओ' की पुरानी धुन में आप एक नयी कड़ी जोड़ेंगे 'अमीरी हटाओ'। इस धुन की रचना करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि बजट में आपको कुछ ऐसे उलटफेर करने या करवाने हैं जिससे जनता को यह महसूस हो कि अब आप अमीरों को दी जाने-वाली रियायतों और उनकी आय में कटौती करके गरीबों की आय बढ़ा रहे हैं या उनको रियायतें दे रहे हैं। फिर आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आम भारतीय गणित में तेज नहीं है। उसे तो बस इतना बताना ही काफी होगा कि वर्तमान बजट में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने ५०० करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। आम आदमी तो ५०० करोड़ रुपए की बड़ी रकम के बारे में सुनकर ही आपसे खुश हो जायेगा। उसे क्या पता की देश की बेरोजगारी का दशमांश भी इस राशि से लाभान्वित नहीं होगा। फिर उसे कोई सही बात बतायेगा भी तो नहीं। हर रोज रेडियो और दूरदर्शन पर आपके हितचिंतक गंभीर मुद्राओं में बजट के गरीबी उन्मूलन और बेरोजगार कार्यक्रमों पर रोशनी डालेंगे, जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा ही और आपका उल्लू सीधा हो सकता है। उन्हें यह कौन बतायेगा कि जो राशि आपने रोजगार के लिए आवंटित की है, यदि उस पूरे का इस्तेमाल रोजगार उपलब्ध कराने में किया जाये, तो भी १० रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ९० दिनों के लिए ही सिर्फ २२ लाख बेरोजगार रोजगार से लग सकेंगे, क्योंकि संप्रति एक व्यक्ति के लिए एक दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए २५ रुपए की जरूरत पड़ती है। फिर बजट में प्रस्तावित रोजगार कार्यक्रमों का लाभ देश के ३६० जिलों में से मात्र १२० जिलों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों से संबद्ध लोगों को पहुंचाना ही आपका मंशा है। यानी देश के प्रत्येक १०० परिवारों में से मात्र १८ परिवारों को यह लाभ मिलेगा। अर्थात लगभग २९० लाख परिवारों के बेरोजगार इससे लाभान्वित होंगे। ऐसे में भी यदि गणना की जाये, तो पता चलेगा कि सिर्फ इतने परिवारों के एक-एक सदस्य को सिर्फ एक दिन का ही रोजगार उपलब्ध कराया जाये, तो ७५ करोड़ रुपए खर्च होंगे। अतः ५०० करोड़ रुपए की धनराशि से २९० लाख बेरोजगारों को मात्र एक सप्ताह के लिए रोजगार दिया जा सकता है। हां, यदि बेरोजगारों की की संख्या घटाकर आधी कर दी जाये, तो १४ दिन तक लोग रोजगार से लगे रहेंगे। खैर, कुछ भी हो ५०० करोड़ रुपए की राशि ढिंढोरा पीटने के लिए तो काफी होगी ही। क्योंकि नयी धुन की मदद से यह बताना आसान हो जायेगा कि अमीरों पर करों का बोझ लादकर ही आपने गरीबों के लिए कार्यक्रम बनाये हैं।

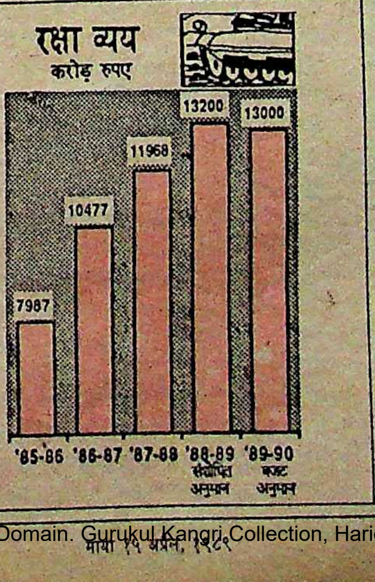

ढोल में पोल: फिर बजट में प्रस्तावित साड़ियां वितरित कराने की योजना का भी कम लाभ आपको नहीं मिलेगा। जबकि सचाई यह है कि बजट में आवंटित २० करोड़ रुपए की इस योजना से संबंधित राशि का चौथाई भाग तो सिर्फ वितरण करने वाली मशीनरी पर ही खर्च हो जायेगा। बाकी बचे रुपए में कितनी कीमत की कितनी साड़ियां खरीदी जा सकती हैं, इसकी गणना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जाहिर है, कम-से-कम कीमत की साड़ी भी २५ रुपए से कम की तो मिलेगी नहीं। इस दर की साड़ियां भी १५ करोड़ रुपए में मात्र ६० लाख ही तो मिलेंगी। जबकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या ५८० लाख है, जिन्हें साड़ियां दिये जाने का प्रस्ताव है। यानी इस योजना के अंतर्गत इस संख्या का दसवां भाग ही लाभान्वित हो सकेगा। फिर भी इस योजना का फायदा तो आपको मिल ही सकता है, बशर्ते रेडियो, दूरदर्शन और आपकी पार्टी के लोग गला-फाड़कर यह चिल्लायें कि वर्तमान बजट में आपने देश के गरीबों का बेहद खयाल रखा है। जाहिर है, इतने परिवारों को लाभ मिले या न मिले, उन्हें यह उम्मीद तो हो ही जायेगी कि आपने जब उनके उत्थान की दिशा में सोचना शुरू कर दिया है, तो किसी न किसी दिन वे आपकी नीतियों से जरूर लाभान्वित होंगे। फिर उनकी यह आशा उस समय और मजबूत होगी जब वे दूरदर्शन के परदे पर आपको किसी मेले में महिलाओं को साड़ियां बांटते देखेंगे। इस दृश्य से धोखे में आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बढ़ा-चढ़ाकर किये गये प्रोपेगंडा से लोगों की धारणा किस हद तक बदलती है। इतना तो है कि जिन भोले-भाले गरीब लोगों को आपने अपना लक्ष्य बनाया है, वे तो बड़ी आसानी से धोखा खा जायेंगे। फिर आपको बाकी लोगों की चिंता भी तो नहीं है। चुनाव जीतने के लिए इतना ही काफी है कि आप हिंदीभाषी राज्यों के गरीब मतदाताओं का रुख अपने पक्ष में कर लें, क्योंकि लोकसभा की ५२६ सीटों में से २०० से ज्यादा सीटें तो हिंदीभाषी राज्यों में ही हैं।

जाहिर है, देश के पांच हिंदीभाषी राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से १५० सीटें भी यदि आपको मिल जाती हैं, तो आपका उल्लू सीधा हो जायेगा। आपको केवल यह ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जिन ६० क्षेत्रों, बिहार के जिन ४० क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के जिन ३० क्षेत्रों तथा राजस्थान के जिन २५ क्षेत्रों से आपको पूर्ण सहयोग मिलने की आशा हो, वहीं आप अपने कार्यक्रमों को लागू करवायें। इन क्षेत्रों के एक करोड़ परिवारों को भी यदि आप अपने कार्यक्रमों का लक्ष्य बना लें, तो भी आप की जीत होगी। किंतु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके उपर्युक्त नये बजट ने देश के ४५ से ५० करोड़ मध्यवर्गीय शहरी परिवारों को नजरअंदाज कर दिया है। यही नहीं, जिन किसानों की पिछले कुछ वर्षों में आमदनी घटी है, वे भी आपसे कुछ नाराज हैं।

किसानों के लिए लालीपाप: बेहतर होगा कि नाराज किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए भी आप कुछ लालीपाप मुहैया करें। किसानों के लिए तो इतना ही काफी है कि आप उनको खाद के इस्तेमाल पर अब तक जो रियायत देते आ रहे थे, उसमें कमी न करें। साथ ही, यदि उन पर अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश न हो, तो उन्हें अधिक से अधिक कर्ज देने की गुंजाइश पैदा कर दीजिये। इसके लिए आपको सिर्फ यही तो करना होगा कि आप आसानी से ऋण उपलब्ध कराने की योजनाए

बजट से फायदा किसको ?

यद्यपि सबको यह उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष होने के नाते प्रधानमंत्री का प्रयास होगा कि वित्त मंत्रालय नर्म बजट पेश करे, किंतु देश के आर्थिक संकट और चरमराती अर्थव्यवस्था का करीब से जायजा लेकर 'माया' ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि चुनावी वर्ष में भी राहत की खास गुंजाइश नहीं। २८ फरवरी को वित्तमंत्री शंकरराव चव्हाण ने ७३३७ करोड़ रुपए घाटे का जो बजट पेश किया उसका एक-एक अंश यह बोल रहा है कि दिवालिया होती सरकार के पास सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं था कि आंकड़ों का उलटफेर करके जनता को धोखा दिया जाये। जाहिर है, भारत जैसे लोकतंत्र में जहां स्थिति यह है कि आज भी साक्षरता सबसे पीछे है, वहां बजट के आंकड़ों की समझ किसको होगी? जो आंकड़ों के खेल को समझ सकते हैं, उन पर तो जाहिर हो गया है कि ८९-९० का बजट चुनावी वर्ष का सबसे बड़ा धोखा है। बजट पेश किये जाने के फौरन बाद रेडियो और दूरदर्शन जिस तरह से खोज-खोजकर बजट के लाभप्रद अंशों पर रोशनी डाल रहे थे, वह इस बात का द्योतक था कि बजट में वास्तविक नरमी का अभाव होने के कारण ही सरकार प्रोपेगंडा का सहारा ले रही है। रेडियो और दूरदर्शन पर बजट के सबसे प्रचारित अंशों में रोजगार और गरीबी हटाओ कार्यक्रम शामिल थे। हालांकि यदि इन अंशों की गहरायी में जाया जाये, तो पता चलेगा कि इन कार्यक्रमों के लिए सरकार ने कांट-छांट और अतिरिक्त करों के प्रस्ताव के सहारे जो राशि आवंटित की है, उससे देश की बेरोजगारी और गरीबी के दशमांश का भी हल नहीं किया जा सकता। फिर आर्थिक संकट और मजबूरी की तो यह स्थिति है कि रक्षा विभाग का बजट बढ़ाने के प्रस्ताव पर ध्यान देना तो दरकिनार, देश के रक्षा बजट में से भी २ अरब रुपए की कटौती करनी पड़ी है। उल्लेखनीय है कि ८८-८९ के बजट में रक्षा के मद में १३, २०० करोड़ रुपए आवंटित किये गये थे तथा इस वर्ष कुल बजट का १४ प्रतिशत ही आवंटित किया गया है।

जहां तक ८९-९० के बजट के नर्म होने की बात थी 'माया' ने १५ मार्च के अंक में 'राहत की सांसत' शीर्षक के अंतर्गत लिखा था, "बहरहाल, यदि राजीव गांधी भी इसी अंदाज में सोच रहे हैं, तो यह निश्चित है कि अगले बजट (८९-९०) में अनेक उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद तथा सीमा शुल्क बढ़ेंगे। उपभोक्ता वस्तुओं में से उन वस्तुओं पर तो विशेष बढ़ोतरी होगी, जिन्हें जरूरत में शामिल नहीं किया जाता।"

महंगाई बढ़ेगी: हुआ भी बिलकुल ऐसा ही। लगभग सभी क्षेत्र में करों में वृद्धि की गयी है। बहुत सारे सामानों पर तो ५ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया है। साथ ही, अनगिनत सामानों के दाम बढ़ाये गये हैं। कुल मिलाकर ८९-९० के बजट का परिणाम मुद्रास्फीति ही है। इस बार तो मुद्रास्फीति की दर पिछले कुछ वर्षों की दरों से अधिक होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ बजट के कारण होगा। असलियत तो यह है कि बजट के हिसाब से अतिरिक्त करों के रूप में १२८७ करोड़ रुपए उगाहे जायेंगे। इस अतिरिक्त आय का ५०० करोड़ रुपया तो प्रत्यक्ष करों के जरिए ही आयेगा। फिर बजट पूर्व ही कुछ चीजों के दाम बढ़ाये गये थे, ताकि ६५० करोड़ रुपए एकत्र किये जा सकें।

वर्तमान बजट के प्रस्तावों की परिणति यह होगी कि व्यापारियों का खर्च बढ़ेगा। इस बढ़ोतरी से गैर व्यांपारी अमीर लोग भी प्रभावित होंगे। जाहिर है, व्यापारियों के खर्च में जो बढ़ोतरी हुई है, उसे वे उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर वसूलेंगे। दूसरी ओर इस्पात महंगा होता जा रहा है। नतीजतन इस्पात के इस्तेमाल से बनने वाले सामान भी महंगे हो जायेंगे। मारुति कारों की कीमत में तो ११,००० रुपए तक की वृद्धि होगी।

कुल मिलाकर जो नतीजें सामने आयेंगे वे अच्छे नहीं होंगे। विद्युत महंगी होगी। गृह निर्माण महंगा हो जायेगा। सिगरेट, पान-मसाला, शराब, इलेक्ट्रानिक के सामान आदि भी महंगे होंगे। उत्पादनों के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इससे बड़ी मार यह है कि इन उत्पादनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का खर्च भी बढ़ जायेगा। क्योंकि रेलवे बजट में तो मालभाड़े बुरी तरह बढ़ाये गये हैं।

अब उन लोगों पर नजर डाली जाये जो आयकर देते हैं। उनको भी बजट ने धोखा दिया है। जिन लोगों की सालाना आय ३६,००० रुपए है और उनकी भविष्य निधि बचत ६,००० रुपए है, तो उनको आयकर में प्रतिमाह २७.५० रुपए की राहत मिलेगी। जिन लोगों की आय ६८,००० रुपए होगी, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। बजट

बनवायें। इस कार्य में आप कृषि एवं ग्रामीण राष्ट्रीय विकास बैंक की मदद ले सकते हैं, जो बैंकों से किसानों को बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध करवा सकता है।

बस इतना सिरदर्द लेने की देर है कि नाराज किसानों को खुश करने के लिए हथकंडे तैयार हो जायेंगे। अब आप बड़े-बड़े मेलों का आयोजन कराकर किसानों को खुश कर सकते हैं, जैसा कि आपने पहले मेले आयोजित कराकर किया है। बेहतर होगा कि प्रत्येक कृषक परिवार को ऋण देने का लक्ष्य बनाया जा जाये भले १०० रुपए प्रति परिवार ही दिया जाये। इसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाये कि हिंदीभाषी राज्यों के केवल उन किसानों को ही लक्ष्य बनाया जाये जहां से १५० सीटें प्राप्त होनी हैं। ऐसा करने से सिरदर्द हल्का रहेगा और कुरसी भी बच जायेगी। यदि ३०,००० किसानों को भी लक्ष्य बनाया गया,तो मात्र ४५ करोड़ रुपए के कर्जों से ही चुनावी लक्ष्य हासिल हो जायेगा।

अब रह जाती है मध्यवर्गीय आबादी। जाहिर है, इसी वर्ग पर महंगाई का सबसे खराब असर पड़ता है। फिर आपके बजट के हिसाब से तो प्रस्ताव के अनुसार ५०,००० रुपए सालाना से अधिक आयवालों को ८ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देना होगा। यानी, जिस व्यक्ति की माहवारी आय ५,७०० रुपए से अधिक होगी उसे ज्यादा आयकर देना होगा। जो इससे कम कमा रहे हैं, किंतु आयकरदाता हैं, उन्हें प्रतिवर्ष २५ रुपए से ३५० रुपए की राहत हासिल होगी। किंतु इस राहत से उनका भला होनेवाला नहीं, क्योंकि महंगाई उनके खर्च बढ़ा देगी और पूरा साल वे परेशान रहेंगे। जो लोग शहरों में भाड़े के मकान में रहते हैं, उन्हें तो ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि वस्तुओं के मूल्य के साथ मकान भाड़ा भी बढ़ेगा।

उपर्युक्त विश्लेषण के बाद सवाल यह उठता है कि जब बजट से किसी को राहत नहीं मिली, तो बजट किसके लिए नर्म है? जाहिर है, सीमेंट उत्पादकों को तो फायदा होगा ही, क्योंकि सीमेंट नियंत्रण मुक्त हो गयी है और उन्हें अभाव का अहसास कराने का बहाना मिल गया है। हालांकि अन्य उत्पादकों को किसी न किसी रूप में बोझ उठाना पड़ेगा। अंतर्देशीय हवाई उड़ानें महंगी हो गयी हैं और होटल खर्च पर लगने वाला कर भी १० प्रतिशत से २० प्रतिशत कर दिया गया है। हो सकता है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों में से कुछ को कोई फायदा मिले, किंतु ज्यादा उम्मीद तो यही है कि देश का आम आदमी तो इस बजट से बुरी तरह प्रभावित होगा, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के लिए तो ८९-९० का बजट निस्संदेह कमरतोड़ होगा। क्योंकि महंगाई का सीधा प्रभाव मध्यमवर्ग पर ही पड़ता है।

—कु०च०

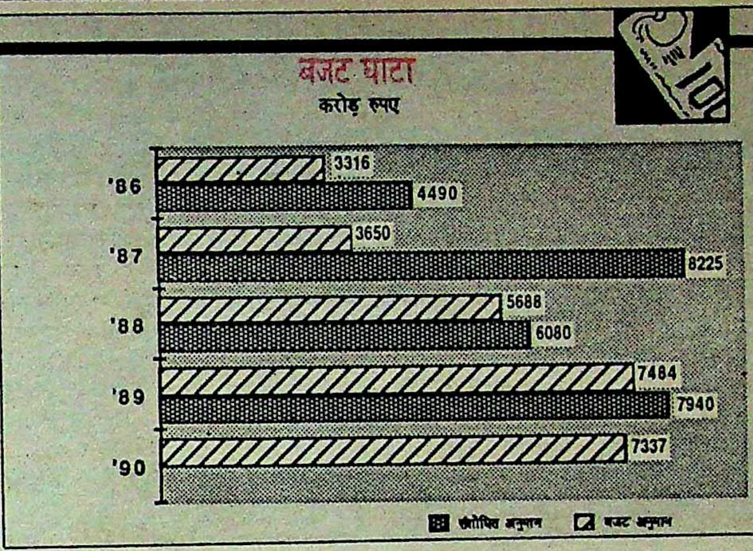

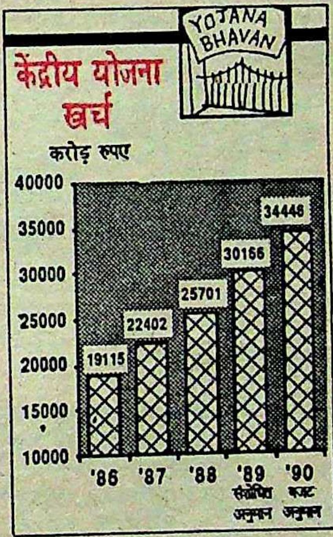

> **आम दिनों में बजट देश का आर्थिक मसला होता है, किंतु चुनावी वर्ष में बजट राजनीतिक हथकंडा बन जाता है। ८९-९० का बजट राजीव गांधी के लिए चुनावी हथकंडा ही है। यह उनकी मजबूरी है कि कुछ न कर सकने की स्थिति में जनता को धोखा देना उनके लिए जरूरी हो गया था।**

उच्च मध्यमवर्गीय परिवारों को टीवी, मारुति, सिगरेट, शराब तथा आयकर आदि का बढ़ा हुआ बोझ सहन करना होगा। जहां तक व्यापारियों की बात है, यदि उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी कर दिया जाये, तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे हैं ही कितने? आपको करना सिर्फ इतना है कि इस साल आप केवल यह रट लगाते रहें कि आपने अमीरी हटाने का संकल्प कर लिया है। जाहिर है, जब आप 'अमीरी हटाओ' का जाप करेंगे, तो लोग यह मानने पर तो मजबूर हो ही जायेंगे कि आप गरीबी हटाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, नतीजतन आपको उनका सहयोग मिल जायेगा।

राजनीतिक हथकंडा: लगता है, बिलकुल इसी तरह राजीव गांधी ने भी सोचा था। क्योंकि जो बजट २८ फरवरी को वित्तमंत्री ने पेश किया है वह भी बिलकुल वैसा ही बजट है जैसा आपने परिस्थित्तियों की चुनौती का सामना करते हुए तैयार किया है। हालांकि आम दिनों में बजट देश का आर्थिक मसला होता है, किंतु चुनावी वर्ष में बजट राजनीतिक हथकंडा बन जाता है। ८९-९० का बजट राजीव गांधी के लिए चुनावी हथकंडा ही है। यह उनकी मजबूरी है कि कुछ न कर सकने की स्थिति में जनता को धोखा देना उनके लिए जरूरी हो गया था। अब तो बस यही उपाय है कि वे जनता को अपनी नयी धुन से मोह लें। जाहिर है, जब तिजोरियां खाली हों और दिवालिया होने की स्थिति करीब हो, तो सिवाय भुलावा देने के और क्या किया जा सकता है? 'अमीरी हटाओ' की उनकी नयी धुन यदि कारगर हुई, तो संभव है उन्हें जनता का सहयोग मिल जाये। किंतु सचाई तो यह है कि ८९-९० के बजट से देश के किसी वर्ग को कोई लाभ मिलने वाला नहीं, अमीर-अमीर रहेगा और गरीब-गरीब। जो अमीरी और गरीबी के बीच जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें जरूर नुकसान पहुंचेगा।

—कुमारेश चक्रवर्ती

ध्यान रखिये!
वाहन समान रफ़्तार से ही चलाइये!

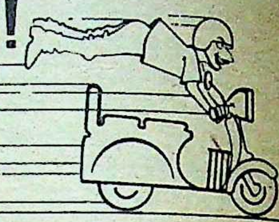

रहें सावधान
हरदम रखें हवा का ध्यान!

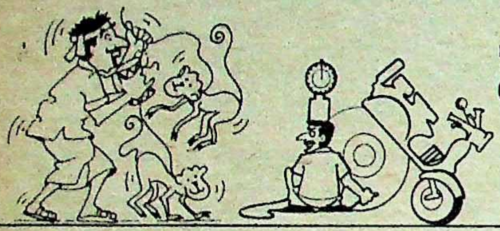

ध्यान दीजिए!
क्लच का सही इस्तेमाल कीजिए!

ध्यान रखें एक बात
इंजन रहे ठीक-ठाक!

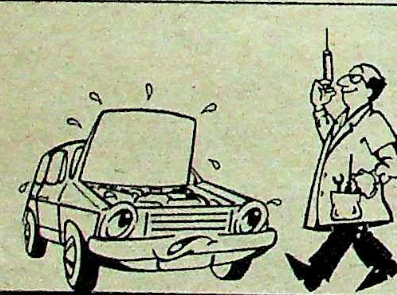

और हर लीटर में ज़्यादा दूरी तय कीजिए !

आप पैट्रोल का दाम नहीं, इसका खर्च ज़रूर कम कर सकते हैं.
आपके वाहन का ईंधन बचाने के लिए कुछ प्रमाणित उपायों पर अमल करके.
ऐसे उपाये जिनसे हर लीटर में ज़्यादा दूरी तय की जा सकती है.

पैट्रोलियम कन्ज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA
1008, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001.

ULKA-D-PCRA-418 HIN

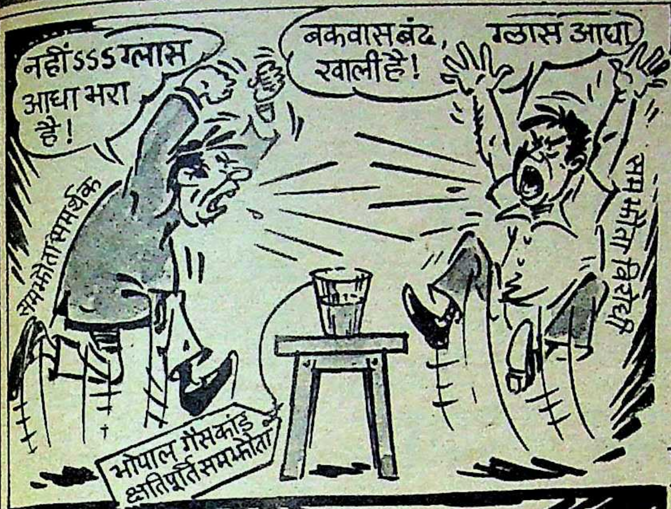
नहींऽऽऽ ग्लास आधा भरा है!
बकवास बंद, ग्लास आधा खाली है!
समझौता समर्थक
समझौता विरोधी
भोपाल गैसकांड क्षतिपूर्ति समझौता

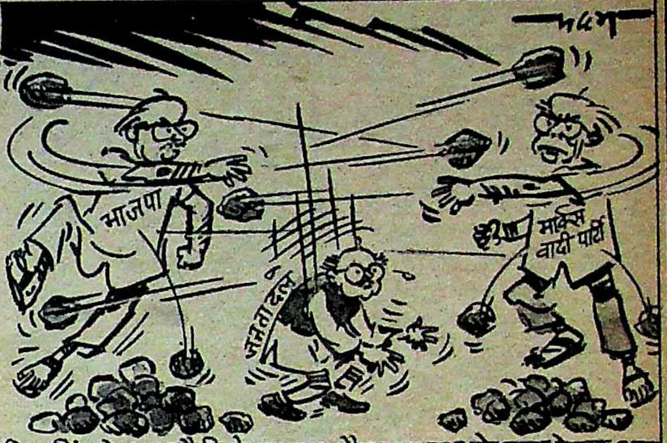
कदम
भाजपा
जनता दल
मार्क्सवादी पार्टी

वि.प्र. सिंह को आशा है कि वे भाजपा और वाम पक्ष को साथ लेकर आम चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने में सफल होंगे —

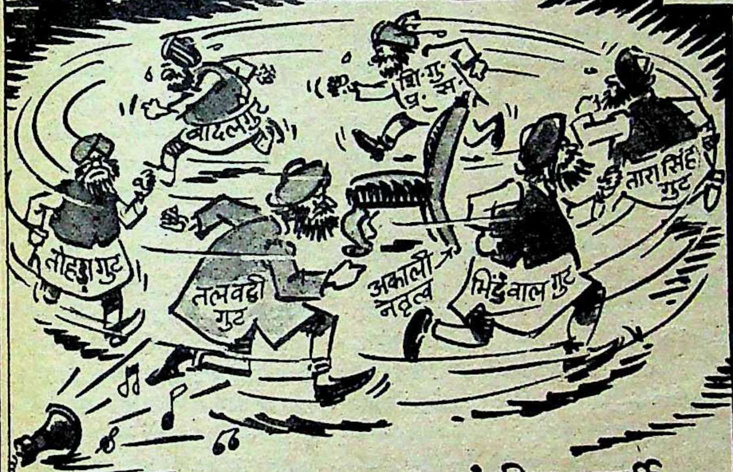
बादल गुट
शि.गु.प्र.स.
तारा सिंह गुट
तोहड़ा गुट
तलवंडी गुट
अकाली नवदल
भिंडरवाल गुट

संगीत-कुर्सी

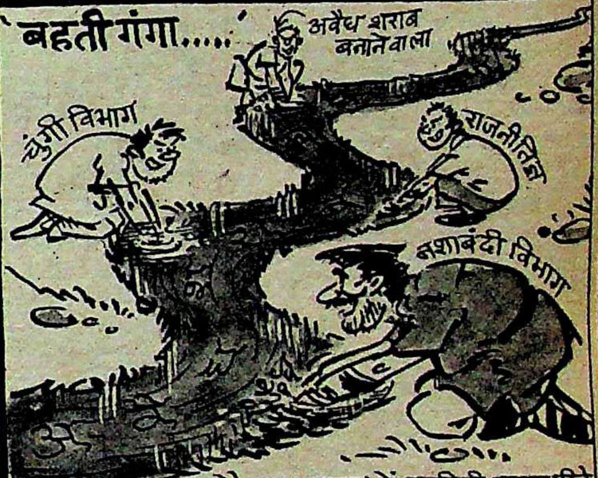
बहती गंगा.....
अवैध शराब बनाने वाला
चुंगी विभाग
राजनीतिज्ञ
नशाबंदी विभाग

बड़ौदा (गुजरात) में जहरीली शराब पीने से १२६ मरे और १०० की हालत गंभीर —

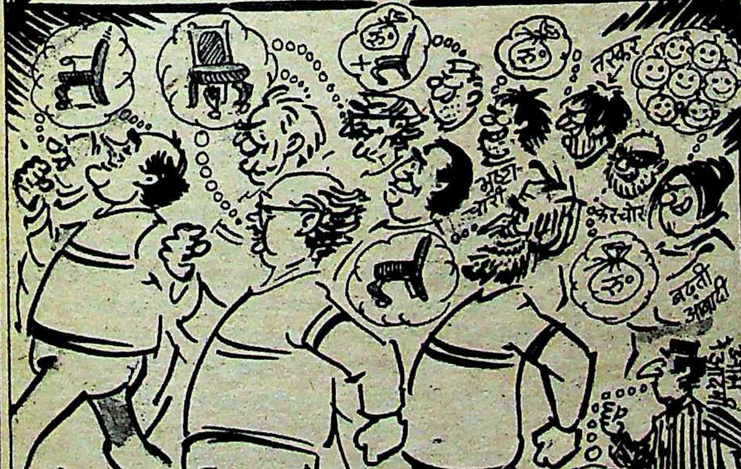
तस्कर
भ्रष्टाचारी
करचोर
बढ़ती आबादी
आम आदमी
भारतीय एकता, समृद्धि आदि

नेहरू जन्म शताब्दी पर देश भर में आयोजित दौड़ संपन्न मगर एक और दौड़ जारी है —

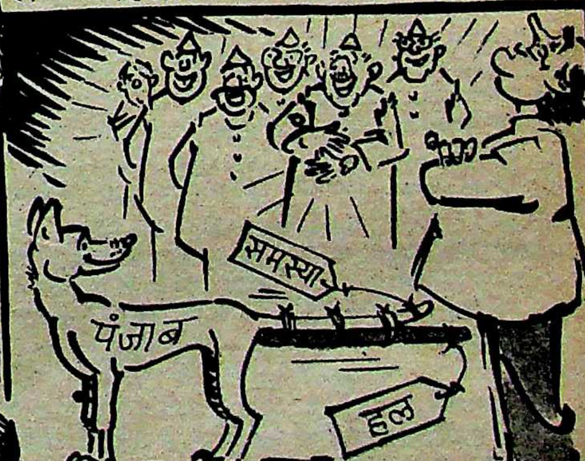

प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंजाब समस्या के राजनीतिक हल की योजना की घोषणा —

माखनलाल चतुर्वेदी

'एक भारतीय आत्मा' की उपेक्षा

'पुष्प की अभिलाषा' शीर्षक कविता की ये पंक्तियां "चाह नहीं मैं सुरबाला के केशों में गूंथा जाऊं..." भारतीय दूरदर्शन के परदे पर आये दिन गूंजती रहती हैं। लोकसेवा संचार परिषद ने इस कविता को जादुई परदे के जरिये जन-जन के हृदय तक पहुंचा दिया है, किंतु इसके प्रणेता स्व० माखनलाल चतुर्वेदी मप्र शासन की उपेक्षा के गर्त से आज तक उबर नहीं सके हैं। 'उत्सवप्रिय नौकरशाही लोकशाही पर हावी है'— भोपाल में माधवराव सप्रे समाचारपत्र संग्रहालय के संस्थापक व संचालक पत्रकार विजयदत्त श्रीधर कहते हैं, "नौकरशाह के मन में मप्र की माटी के सपूतों और गौरवपुरुषों के प्रति अनुराग व श्रद्धा कहां?" श्रीधर स्व० चतुर्वेदी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने की दिशा में सक्रिय हैं। वे दादा (माखनलाल चतुर्वेदी) के विस्मरण को अकारण नहीं मानते। उनका तर्क है कि यह विस्मरण इसलिए है, क्योंकि उनके नाम पर नौकरशाहों के लिए पाखंड रचने की गुंजाइश नहीं है।

श्रीधर की बात सही है। खरी बात अकसर कटु होती है। मध्यप्रदेश न्यासों, पीठों, अकादमियों का प्रदेश है, और उसे 'कलाओं के घर' का तमगा प्राप्त है, मगर दादा (माखनलाल) के नाम पर न तो कोई स्मारक है, न ही कोई पीठ। संस्कृति विभाग हर साल कला और संस्कृति के नाम पर लाखों रुपए के पुरस्कार बांटता है, किंतु पत्रकारिता अथवा सोद्देश्य लेखन के लिए माखनलालजी जैसे समादृत क्रांतिकारी व साहित्यकार के नाम पर माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार घोषित करने का खयाल लगता है कि मप्र शासन के जेहन में आया ही नहीं।

पुण्यसलिला नर्मदा के तट पर बसे होशंगाबाद जिले में भोपाल से करीब १२५ किमी दूर स्थित है बाबई। फिलवक्त इसकी आबादी करीब १५ हजार है। यही बाबई दादा का जन्मस्थान है। यहीं ४ अप्रैल, १८८९ को शिक्षक नंदलाल के यहां उनका जन्म हुआ था। १९०७ में वे खंडवा चले गये। १९२०-२४ के जबलपुर अथवा जेल प्रवास तथा छह माह के लिए कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के 'प्रताप' के संपादन को छोड़ दें, तो ३० जनवरी, १९६८ को देहांत तक खंडवा दादा की कर्मभूमि रहा। अपने लंबे जीवन में उन्होंने 'कर्मवीर' और आजादी की लड़ाई में अपनी शिरकत से जो अलख जगायी, उसकी आंच आज भी महसूस की जा सकती है। उनकी महत्ता व प्रतिष्ठा का पता इससे लगता है कि महात्मा गांधी १९३२ में इटारसी आने पर यह कहकर जिद कर बाबई गये थे कि वह उस माटी को नमन करना चाहते हैं जहां दादा जनमे हैं। दादा के अनूठे व्यक्तित्व में वस्तुतः तीन गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण था। वे क्रांतिकारी कवि, प्रखर संपादक और ओजस्वी वक्ता थे। उनके घर व छापेखाने की ६३ बार तलाशियां ली गयीं और वे बारह बार कारावास गये। दादा की वक्तृत्व शक्ति के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम सब लोग बातें करते हैं, बोलना तो माखनलालजी जानते हैं। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 'कर्मवीर' ने राष्ट्रीय महासभा के झंडे को ऊंचा रखा है। बरसों पत्रकार रहे वर्तमान मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा कहते हैं, "माखनलालजी मप्र में स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य और पत्रकारिता तीनों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं।"

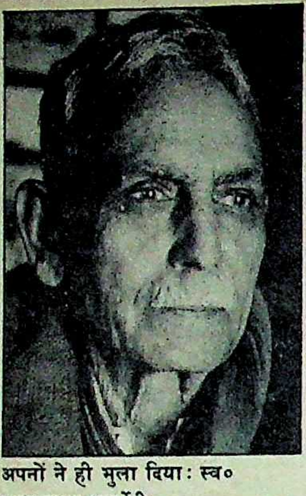

अपनों ने ही भुला दिया : स्व० माखनलाल चतुर्वेदी

अपने राजद्रोहात्मक भाषण के कारण दादा ब्रिटिश सरकार के कोपभाजन भी बने। सजा भुगतते हुए बिलासपुर जेल में उन्होंने १८ फरवरी, १९३२ को 'पुष्प की अभिलाषा' नामक प्रसिद्ध कविता लिखी, परंतु विडंबना, मप्र शासन की विस्मरण वृत्ति और क्रूर मजाक देखिए कि आजादी के बाद बिलासपुर के कारागार में आजादी के दीवानों का नामपट्ट लगाया गया, तो उसमें दादा का नाम नदारद था। जब होहल्ला मचा, तो उनका नाम जोड़कर भूल का परिमार्जन किया गया, मगर उनका कैदी नंबर १५२७ अभी अनंकित है।

प्रेरणाप्रद : कायदे से देखें, तो दादा का नाम समस्त कांग्रेसी नेताओं, हिंदीप्रेमियों और भाषायी पत्रकारों के लिए स्मरणीय व प्रेरणाप्रद है। १९२० के असहयोग आंदोलन में मध्यप्रांत से केवल तीन लोग बंदी बनाये गये थे : माखनलाल चतुर्वेदी पं० सुंदरलाल और महात्मा भगवानदीन। चूंकि, सुंदरलाल व भगवानदीन क्रमशः प्रयाग व नागपुर के थे, अतः कहना चाहिए कि महाकौशल के अकेले गौरवपुरुष दादा थे। इसी भांति सन ३० के आंदोलन में मध्यभारत में गिरफ्तार पहले पांच व्यक्तियों में सेठ गोविंददास, पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र, रविशंकर शुक्ल, विष्णुदयाल और दादा थे। सन ३७ में दादा कांग्रेस के पार्लियामेंटरी बोर्ड में थे। उनके अत्यंत निकट रहे पं० रविशंकर शुक्ल व द्वारकाप्रसाद मिश्र कालांतर में मुख्यमंत्री बने, लेकिन दादा की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के सार्थक उपक्रम की ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर दादा के तेवर देखिए कि सन ६७ में राजभाषा विधेयक के विरोध में उन्होंने पद्मविभूषण की उपाधि लौटा दी। माखनलालजी पत्रकारिता के नैपोलियन बोनापार्ट कहलाते थे। खंडवा में जवाहर गंज में वे दोनों एकमंजिले मकान आज भी अवस्थित हैं, जिनमें एक में दादा रहते थे और दूसरे में छापाखाना था, जहां 'कर्मवीर' छपता था। दादा का मकान उनके जीतेजी क्रांतिकारियों, बौद्धिकों और राजनेताओं के लिए तीर्थ बन गया था। डीपी मिश्र के कुलपतित्व काल में सागर विवि ने जब उन्हें डीलिट की उपाधि दी, तो परंपरा तोड़कर खंडवा में समारोह किया गया। पहले डीपी मिश्र और फिर उनके शिष्य अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने यह नहीं किया कि दोनों मकानों को शासन अधिगृहीत कर वहां दादा की स्मृति, उनके अवशेषों, स्मृतिचिह्नों, कृतियों, पाडुलिपियों और अन्य दस्तावेजों को सहेज दिया जाये। सन ६३ में खंडवा में अनेक हस्तियां उमड़ीं और इससे संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं रेंगने में लगभग दस साल लगे। सन ७३ में मप्र शासन ने तत्संबंधित एक कागजी आदेश जारी किया था, लेकिन सोलह साल होने को आये, अमल तो दूर, उस पर अमल के आसार आज भी नजर नहीं आते। ताजा स्थिति यह है, जिसकी जानकारी पता नहीं शासन को है या नहीं, कि किन्हीं चटर्जी महाशय का वह मकान जिसमें दादा रहते थे, किसी ने खरीद लिया है और उसमें पर्याप्त फेरबदल भी हो गया है।

स्व० माधवराव सप्रे दादा के अभिन्न सहयोगी थे, उनकी स्मृति में भोपाल में समाचारपत्रों का अनूठा संग्रहालय स्थापित है। २७ मार्च, '८८ को संग्रहालय की संदर्भ सूची के विमोचन प्रसंग पर श्रीधर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से मांग की थी कि बाबई को माखननगर व मुंगावली को गणेशशंकर विद्यार्थी नगर नामकृत किया जाये। १४ अप्रैल को स्पीकर राजेंद्र शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष कैलाश जोशी व विधायक बाबूलाल गौर ने ध्यान आकृष्ट किया, तो अर्जुन सिंह ने बाबई के माखननगर नामकरण, वहां स्मारक निर्माण तथा इस मौके पर राज्यस्तरीय समारोह आयोजित

दादा की चिता : विजयदत्त श्रीधर

करने की घोषणा की। इस बात को एक साल होने को आया। नतीजा ढाक के तीन पात है। गत दिनों 'माया' संवाददाता ने जब बाबई का दौरा किया, तो पाया कि पूरे नगर में कहीं भी माखननगर का नामपट नहीं लगा है। सन ६३ के करीब जब बाबई के युवकों ने दादा का जन्मदिन मनाना शुरू किया था, तो दादा ने श्रीकांत जोशी से बाबई के युवकों को प्रणाम लिखवाया था। यहीं कस्बे में टाउन कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कृष्णकुमार से मुलाकात हुई। बड़े-बूढ़ों के हवाले से उन्होंने बताया कि दादा उस जमाने में हरिजनों के साथ बैठकर भोजन करते थे। करीब दो दशक पहले दादा का अस्थिकलश धूमधाम से खंडवा से बाबई लाया गया था। यह सुनकर कलश के दर्शनों की चाह मन में अनायास उत्पन्न हुई। कस्बे के एक अध्यापक बंधु के साथ धूलधूसरित रास्ते से होकर बमुश्किल वाचनालय पहुंचे, तो यह देखकर अवाक रह जाना पड़ा कि जर्जर व उपेक्षित वाचनालय में बाहर ताला जड़ा है। पेशाब, मल और विष्ठा से आच्छादित पीछे के रास्ते से जाकर कपाटविहीन खिड़कियों से झांका, तो पाया कि अंदर गंदगी, सन्नाटे और चमगादड़ों का वास है। पिछवाड़े की खिड़की से फांदकर भीतर प्रवेश किया, तो माचिस की टिमटिमाती रोशनी में जो दृश्य उजागर हुआ, उसने महामनीषियों के प्रति समाज व सरकार की सोच व सलूक की कलई खोल दी। सिर शर्म से झुक गया। वाचनालय में एक भी किताब नहीं थी। एक आलमारी जरूर थी। सोचा शायद उसमें अस्थिकलश हो, पर कलश भी नदारद था। दादा का अस्थिकलश अब कहां होगा, कहा नहीं जा सकता। पता नहीं, वह सुरक्षित है भी या नहीं।

उपर्युक्त प्रश्न का किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। वाचनालय के प्रबंधक बाबूलाल डहेरिया और भवन के स्वामी धनराज खंडेलवाल उपलब्ध नहीं थे कि कोई नयी जानकारी मिलती। क्षेत्रीय विधायक काकू भाई (विजय दुबे) से अवश्य चर्चा हुई। वे वोरा सरकार में गृह, सामान्य प्रशासन एवं जनसंपर्क विभाग के उपमंत्री हैं। सफायी के लहजे में बोले, "दादा को हम भूले नहीं हैं, किंतु क्या करें? बाबई के माखननगर नामकरण के बारे में केंद्रीय गृहमंत्रालय को लिखा गया है। पत्राचार व औपचारिकता के निर्वाह में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है।" 'माया' ने जब पड़ताल की, तो ज्ञात हुआ कि मप्र शासन ने गृहमंत्रालय एवं निर्वाचन आयोग को काफी विलंब से प्रतिवेदन भेजा है। २४ जून '८८ को शासन ने राज्य स्तरीय समिति की घोषणा की थी। मजे की बात है कि इस कमेटी की न तो आज तक कोई बैठक हुई है और न ही इसके सदस्यों को विधिवत सूचना भेजी गयी है। आगामी ४ अप्रैल को एक भारतीय आत्मा यानी स्व० माखनलाल चतुर्वेदी की १०१वीं जन्म तिथि है। जन्मशती वर्ष के बीतते-बीतते सरकार चेत जायेगी, आसार कम ही हैं। माखननगर नामकरण की औपचारिकता को पूरा कर वहां स्मारक बनाने, वहां आदमकद या आवक्ष प्रतिमा स्थापित करने तथा खंडवा में मकानों को अधिगृहीत कर वहां संग्रहालय व स्मारक भवन तथा क्रांतिकारी साहित्य व स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास पर केंद्रित शोधकेंद्र खोलने के संदर्भ में कहा जा सकता है कि सरकार के पास न दृष्टि है, न समय। जलसों में महान विभूतियों का नाम लेना व उनके आदर्शों का बखान करना सरकारी नुमाइंदों व नौकरशाहों के लिए जितना आसान है, उन्हें भूलना उनके लिए इससे कहीं ज्यादा आसान है।

—सुधीर सक्सेना, बाबई से

प्रेम-अपराध कथा विशेषांक

मनोहर कहानियाँ

अप्रैल, '८९

दो लड़कियों की
प्रेम कहानी बनाम
यौन-परिवर्तन

दिल्ली की दो लड़कियों,
मंजु और मधु के बीच प्रेम इतना गहराया
कि उन्होंने कभी जुदा न होने का
फैसला कर लिया।

अंधेरे में उजाला

पटना के एक नेत्रहीन,
किन्तु प्रतिभाशाली अंग्रेजी प्रवक्ता
और एक सुशिक्षित युवती के
प्रेम-विवाह की प्रेरक कथा।

नीतू और पटना के
एक इंजीनियर का पत्र

पहले पति से त्रस्त नीतू अपनी मां
और मौसी के पास
पटना क्या आयी कि एक कथित सेक्स-स्कैण्डल
में फंस गयी, फिर एक इंजीनियर ने उसे
नौकरी और घर के साथ संरक्षण
दिया, तो नया स्कैण्डल उठ खड़ा हुआ।

जीत : प्रेम कथा
जो सुप्रीम कोर्ट तक
जा पहुंची

दिल्ली के एक युवक
और एक युवती ने अपने प्यार को
मंजिल तक पहुंचाने के लिए
शादी तो कर ली,
लेकिन उनके दाम्पत्य-जीवन में
ऐसे टकराव, तनाव और
कानूनी मुद्दे आये कि उन्हें
सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।

अन्य अनेक मर्मस्पर्शी एवं सत्य प्रेम-कथाएं

बजट की मारी गृहिणी

नये बजट के साथ-साथ मेरी भाषा और शैली दोनों के लिए चुनौती खड़ी हो गयी है। अब तक किसी को उम्र बतानी होती थी, तो बड़ी शिष्ट शैली में कह दिया करती थी 'हमने इतने वसंत देखे हैं।' इसमें दो-चार वसंत की चोरी भी आसानी से खप जाती थी। लेकिन अब तो कहना पड़ेगा, हमने अब तक इतने बजट देख लिये हैं। बजट से गुजरा इंसान किसी भी तरह का झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकता। बजट-भुक्त आदमी बजट-मुक्त आदमी से बिलकुल अलग किस्म का होता है। जिसे घर चलाने के दौरान अट्ठारह-बीस बजट की चपेट में आने का दुर्भाग्य मिल चुका है, उसकी सूरत शक्ल एकदम बदल जाती है। बजट पेश होने की शाम घर का आलम क्या कहिये? पति के कान रेडियो से, आंखें टीवी से जुड़ी बैठी हैं, महीने का आखिरी दिन है, पत्नी चीनी चाय पत्ती के खाली डब्बों में झांक रही है, बच्चे अपनी नयी-नयी जरूरतें होठों में दबाये पिता के चेहरे के आते-जाते रंग देख रहे हैं। बजट से जरा पहले तक पिता हंसते थे, मां किताब कापी के नाम पर एक दो रुपए दे दिया करती थीं, पहली तारीख को घर में मिठाई आती थी...। लेकिन अब यह परिवार यह सब भूल चुका है। उसने नवीनतम बजट देख लिया है। वित्त मंत्री लाख उसे समझायें कि उसके ऊपर किसी नये अथवा प्रत्यक्ष कर का बोझ नहीं बढ़ाया गया है, उसकी आशंका दूर नहीं होती। उसे पता है अगली सुबह से ही बाजार में आग लग जायेगी। जब माल भाड़ा बढ़ा है, तो हर चीज का दाम अपने आप बढ़ जायेगा। बजट से पहले सरकार चीनी, चावल और कोयले के दाम खुद बढ़ा चुकी है। मामूली आदमी की आमदनी आयकर के नीचे चाहे आये न आये, उसका अस्तित्व अवश्य अप्रत्यक्ष करों के बोझ के नीचे पिसता जा रहा है। इस मामूली आदमी की मुश्किल यह है कि वह अपनी किचकिचाहट को आवाज भी नहीं दे सकता, क्योंकि बजट का बस्ता खुलते ही एक वफादार टीम ने 'बहुत अच्छे, बहुत अच्छे' कह कर इस प्रस्ताव को शाबाशी भी दे दी है। सब समर्थकों ने एक स्वर से घोषित किया है कि यह भलमनसाहत भरा जनता का हितू बजट है।

पहलू में बैठी स्त्री सोच रही है, आनेवाले दिन उसकी गृहस्थी के लिए कैसे होंगे? पिछला पूरा साल कैसे बीता है कोई उससे पूछे। एक-एक कर हर चीज पर बिजली गिरी है। दूध, दही, मक्खन, फल तो जीवन से विदा हो ही चुके थे, घी की जगह वनस्पति और वनस्पति की जगह तेल ने ले ली थी। अब अगर तेल के दाम भी बढ़ गये, तो वह क्या पानी में छौंक कर सब्जी चढ़ायेगी? छोटा बेटा चीनी का चींटा है, रोटी चीनी से खाता है, अब क्या चीनी की जगह नमक-रोटी देनी होगी? एक आध छोटी-मोटी ऐयाशी वह भी करने की शौकीन थी। बाजार से सौदा सुलफ लाते पान मसाले की पुड़िया वह अकसर खरीद लेती थी और कभी-कभी पति पर ज्यादा प्यार उमड़ा, तो उसके लिए सिगरेट की डिब्बी। पति चाय के साथ सिगरेट पाकर प्रसन्न हो जाता था। ये सारे शौक यह बजट उड़ा कर ले जायेगा। वह अपने को समझाने की कोशिश करती है, 'सरकार तुम्हारा और तुम्हारे पति का स्वास्थ्य सुधारना चाहती है। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पान मसाला दांतों के लिए।' लेकिन तसल्ली नहीं होती। तबीयत भन्ना रही है—यह क्या कि बड़े बलिदान भी हम करें और छोटे बलिदान भी हमीं। हमारे ही सुख, सपने और सुरूर पर कैंची चलती रहे। दफ्तर में पति के महंगाई भत्ते में पच्चीस-पचास रुपए बढ़ जायेंगे, पर महंगाई इस भत्ते को धता बतायेगी। पत्नी ने अर्थशास्त्र की मोटी-मोटी किताबें नहीं पढ़ीं, लेकिन वह भी समझती है कि जब तक सरकार घाटे का बजट बनाती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, रुपए की कीमत घटती रहेगी। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार वेतनमान में संशोधन करेगी, ऋण-मेले आयोजित करेगी, लेकिन आम आदमी फिर भी रुआंसा घूमेगा। उसका घरेलू जीवन दिन पर दिन बदरंग होता जायेगा।

रंग शब्द स्त्री चेतना पर टंकार की तरह पड़ता है। कोने में यह जो काला सफेद टीवी खड़ा है, उसे बड़ा मनहूस लगता है। जीवन सतरंगी होता है, काला-सफेद नहीं। न जाने कब से वह इसके बदले रंगीन टीवी लेना चाहती है, किंतु टीवी पर आती टीवी की कीमतें इन इरादों के पंख कतर रही हैं। इस बार का बजट उसकी जिंदगी से रस, रंग, रूप, संगीत, स्वाद, गति सब निकाल बाहर करेगा। कई बार स्त्री को लगता है यह बजट एक चिकनी दीवार है और वह स्वयं चींटी, जो लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और लगातार नाकामयाब होती है। बल्कि हर साल ऊपर चढ़ने की जद्दोजहद में कुछ और नीचे फिसलती जाती है। वह उस विशाल अभिशप्त वर्ग की प्राणी है, जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। हर बार फिसल-फिसल कर गिरते-गिरते वह अब निम्न वर्ग में पहुंच चुकी है। वह अपने पति के चिंतित चेहरे की तरफ देख कर मन-ही-मन फैसला करती है कि चाहे कितनी छोटी सी हो, वह नौकरी करेगी। अब वक्त आ गया है कि गाड़ी का दूसरा पहिया भी सरपट दौड़े। बजट के बावजूद गृहस्थी चलानी है।

—ममता कालिया

पत्नी ने अर्थशास्त्र की मोटी-मोटी किताबें नहीं पढ़ीं, लेकिन वह भी समझती है कि जब तक सरकार घाटे का बजट बनाती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, रुपए की कीमत घटती रहेगी। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार वेतनमान में संशोधन करेगी, ऋण-मेले आयोजित करेगी, लेकिन आम-आदमी फिर भी रुआंसा घूमेगा। उसका घरेलू जीवन दिन-पर-दिन बदरंग होता जायेगा।

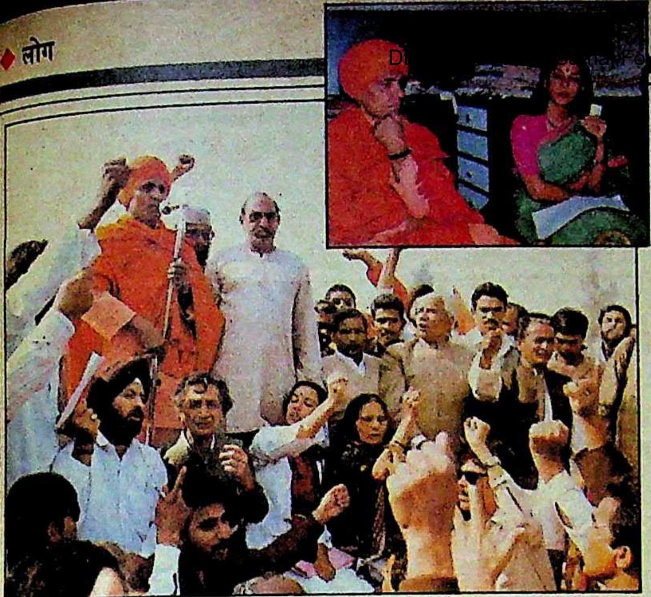

अग्निवेश और शबाना (इनसेट) के साथ पदयात्री दल

शबाना-अग्निवेश

'निवाराहक सुरक्षा समिति' बनाकर बंबई के झोंपड़पट्टी-वालों को हक दिलवाने के लिए प्रदर्शन और अनशन करके जहां शबाना आजमी ने अपने को वंचितों के हकों के लिए लड़नेवाली योद्धा के रूप में स्थापित किया है, वहीं रंगकर्मी सफदर हाशमी की हत्या पर सरकारी मंच से सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में रोष प्रकट करके अपनी निर्भीकता का भी परिचय दिया है। संभवत: अभिनेत्री नरगिस के बाद शबाना आजमी पहली अभिनेत्री हैं, जो सामाजिक-रचनात्मक कार्यों की ओर फिल्मी व्यस्तता के बावजूद सक्रिय हैं। तभी तो ये खबरें उड़ रही हैं कि वे आजमगढ़ या मेरठ से आगामी लोकसभा का चुनाव लड़नेवाली हैं। पर इसमें सचाई कितनी है—यह तो समय बतायेगा? लेकिन आर्य-समाजी नेता स्वामी अग्निवेश के साथ सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दिल्ली के लाल किले से मेरठ तक की चार दिवसीय ९० किमी पदयात्रा ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिये हैं।

वैसे तो इस पदयात्रा में साहित्यकार भीष्म साहनी और करतार सिंह दुग्गल, असगर अली, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता शंकर गुहा नियोगी, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेता शमशेर सिंह विष्ट, भारतीय किसान यूनियन के नेता (मेरठ) मौलाना फिरोजुद्दीन तथा आल इंडिया सिख कांफ्रेंस के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बब्बर सहित २०० प्रमुख व्यक्तियों ने हिस्सेदारी की। पर स्वामी अग्निवेश और शबाना आजमी की अगुवाई में आयोजित इस पदयात्रा को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। लेकिन स्वामी अग्निवेश ने इस पदयात्रा को गैरराजनीतिक पदयात्रा कहा है। बकौल उनके, "इस पदयात्रा का उद्देश्य गरीबी तथा सामाजिक और आर्थिक विषमता के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी ताकतों की एकजुटता की आवश्यकता को उजागर करना था।" शबाना ने भी चर्चाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य सांप्रदायिकता से संघर्ष करने का आह्वान था। दिल्ली से मेरठ की पदयात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भविष्य को बनाना नहीं था। उनका मानना है कि वे सामाजिक चेतना को जागृत करने की दिशा में काम कर रही हैं। किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हैं। पदयात्रा को गैरराजनीतिक मानते हुए वे कहती हैं कि देश के बुद्धिजीवी एक मंच पर खड़े होकर सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें।

रामलाल गुप्ता

संघर्ष की शख्सीयत

कला उम्र की मोहताज नही होती और प्रतिभा हो, तो वह दबी नहीं रह सकती। एक-न-एक दिन वह पल्लवित हो ही जाती है। फिर इरादा पक्का हो, कला के प्रति सच्चा समर्पण हो, तो व्यक्ति अपनी पहचान बना ही लेता है। एक ऐसी ही शख्सीयत हैं रामलाल गुप्ता, जो अपने उम्र (५२ वर्ष) के ऐसे दौर में अपनी कला-प्रतिभा से पहचान बनाने में लगे हैं, जिस उम्र तक आदमी पहुंचते-पहुंचते चुक जाता है, थक जाता है संघर्ष करते-करते। पर रामलाल गुप्ता ने परिस्थितियों के अनेक झंझावात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। परिणाम हुआ टीवी सीरियल 'महाभारत' में उग्रसेन की भूमिका में वे टीवी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए।

मेकअप के पहले (दायें) और मेकअप के बाद रामलाल गुप्ता

'महाभारत' के एपीसोड १०, ११, १२ एवं १८ में उग्रसेन की भूमिका में रामलाल गुप्ता को तो दर्शकों ने देखा ही है, अब टीवी दर्शक उन्हें एपीसोड २३ से २६ तक पुनः देख सकेंगे। श्याम बेनेगल निर्मित-प्रदर्शित सीरियल 'भारत एक खोज' के ७वें एपीसोड में महर्षि वाल्मीकि तथा 'रामायण' के ४७वें एपीसोड में रावण के एक मंत्री हस्तिमुख की भूमिका में भी रामलाल गुप्ता टीवी के परदे पर आ चुके हैं।

आवाज का जादू: टीवी के परदे से फिल्मी परदे की ओर कदम बढ़ाने की ललकवाले रामलाल गुप्ता वर्षों से परदे के पीछे से अपनी आवाज देते रहे हैं। फिल्म 'रजिया सुल्तान', 'राजपूत', 'श्रीमान', 'तीसरी आंख', 'बगावत' आदि फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। फिल्म डिवीजन की कई फिल्मों में कमेंट्री भी की है। इसके अलावा फिल्मों में जगह पाने की गरज से उन्होंने फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिकाएं अभिनीत की हैं, जिनमें प्रमुख हैं—'मजदूर', 'कयामत', 'हम रहे न हम' और 'जियो तो ऐसे जियो।' रंगमंच से अपने अभिनय-जीवन की शुरुआत करनेवाले रामलाल गुप्ता १९६० से १९८० तक रंगमंच पर सक्रिय रहे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के नाटकों में भी समय-समय पर भाग लेते रहे। ८ वें दशक में परदे पर मुखातिब होने की इच्छा से उन्होंने बंबई की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन संघर्ष के साथ-साथ अपने स्वाभिमान को भी कायम रखा। आज जहां भी वे पहुंचे हैं, अपने बलबूते पर।

'महाभारत' से चर्चित होनेवाले रामलाल गुप्ता शीघ्र ही कई टीवी सीरियलों और फिल्मों में दिखलायी पड़ेंगे, जिनमें प्रमुख हैं—चेतन आनंदकृत टीवी सीरियल 'परमवीर चक्र' तथा अशोक गायकवाड़ की फिल्म 'गुनहगार' और बीआर चोपड़ा की 'कल की आवाज'। इलाहाबाद (रंगमंच) से बंबई (दूरदर्शन एवं फिल्म) का फासला तय करनेवाले रामलाल गुप्ता की शख्सीयत का सबसे दमदार पक्ष यह है कि वे जीवन के सच को नकारते नहीं हैं। संघर्ष ही उनका तानाबाना है, जिससे वे कला का फूल खिलाना चाहते हैं। —दिनेश दीनू

साक्षात्कार/श्रीदेवी

नंबरवन का खिताब क्या बला है?

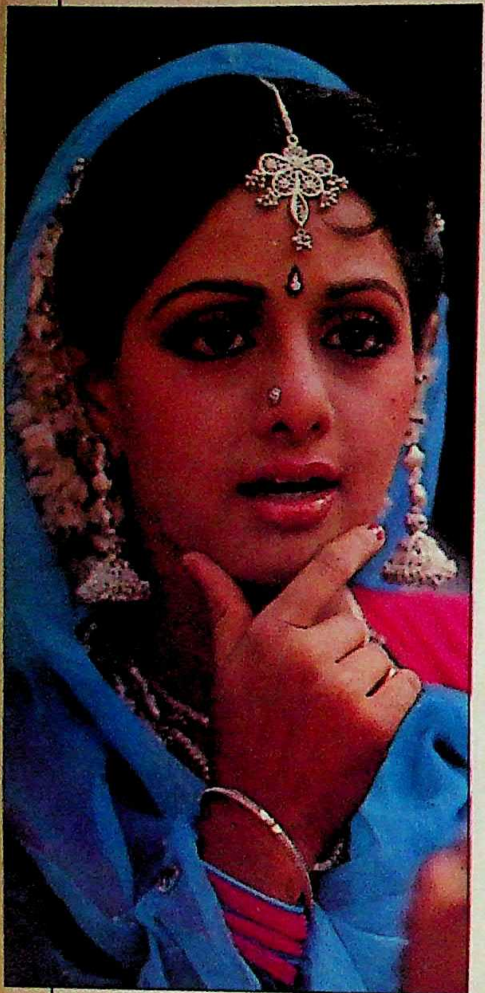

छाया: डीआर यादव

'सोलहवां सावन' से हिंदी फिल्मों में प्रवेश कर तहलका मचानेवाली श्रीदेवी इधर पांच सालों में ऐसी अभिनेत्री साबित हुई है जिसे बाक्स आफिस की लक्ष्मी ही नही, यहां तक कहा गया कि यदि वह स्टूडियो में पड़े किसी पत्थर को भी छू दे, तो वह कामयाब हो जाता है। श्रीदेवी के बारे में सारी फिल्मी पत्रिकाओं ने एक स्वर में ऐलान किया कि ऐसी अभिनेत्री पहले कभी नहीं हुई, जो फिल्म के हीरो से ज्यादा पारिश्रमिक लेती हो और जिसका दूसरा नाम सफलता की गारंटी हो। 'मिस्टर इंडिया' और 'नगीना' जैसी फिल्मों की धुआंधार सफलता ने श्रीदेवी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। फिल्मों में हीरो पर दर्शकों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना श्रीदेवी के लटकों-झटकों पर। फिर यह बात आम हो गयी कि श्रीदेवी का एक झटका लाखों का वारा-न्यारा करने के लिए काफी है। एक समय तो ऐसा भी आया, जब फिल्म उद्योग का बड़े से बड़ा हीरो उसके साथ काम करने के लिए लालायित रहा। और, छोटे से बड़े तक तमाम निर्माताओं की भीड़ उसे साइन करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड गयी। श्रीदेवी की सफलता का पहला झटका जमी जमायी अभिनेत्री रेखा को लगा। अत्यंत सुंदर मानी जाने वाली दक्षिण की ही अभिनेत्री जयाप्रदा पूरे दमखम के साथ श्रीदेवी से टक्कर लेती रही, लेकिन उसके बराबर आने के बाद अचानक पिछड़ गयी। फिर बीच में दो तीन अभिनेत्रियों जैसे भानुप्रिया, मंदाकिनी वगैरह से उसका मुकाबला किया गया, लेकिन वे भी श्रीदेवी का बाल बांका नहीं कर सकीं। फिर डिंपल कपाड़िया में वैसी ही संभावनाएं खोजी जाने लगीं, जो श्रीदेवी को पछाड़ने के लिए काफी थीं। डिंपल की एक दो फिल्मों ने बाक्स आफिस पर अच्छा मुनाफा भी कमाया, मगर महेश भट्ट की 'काश' ने डिंपल को पीछे धकेल दिया और श्रीदेवी अपने नंबर वन सिंहासन पर शान से बैठी रही।

व्यावसायिक फिल्मों में अमिताभ बच्चन जैसी जगह बनाने वाली श्रीदेवी ने पहली बार यह साबित किया कि पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग में सिर्फ हीरो की ही नहीं चलती, हीरोइन भी निर्माता को उंगलियों पर नचा सकती है। अमिताभ बच्चन की फिल्म को यह कह कर ठुकरा देना कि इसमे हीरोइन का कोई 'स्कोप' नहीं, यह श्रीदेवी की ही दिलेरी का सबूत है।

लेकिन अब उसी श्रीदेवी के नाम पर निर्माता-निर्देशक भौंहें सिकोड़ लेते हैं। इसका कारण है 'नगीना' और 'मिस्टर इंडिया' के बाद श्रीदेवी की जो भी फिल्में पिछले साल रिलीज हुई, उनमें से कुछ तो एक सप्ताह भी नहीं चल पायीं और कुछ ने दूसरे दिन ही दम तोड़ दिया। 'राम अवतार' और 'शेरनी' जैसी भारी-भरकम बजट वाली भव्य फिल्मों की भयानक दुर्गति ने निर्माता और बड़े-बड़े वितरकों के होश गुम कर दिये। यह धारणा दिनोदिन जोर पकड़ती चली गयी कि श्रीदेवी का जादू अब पूरी तरह टूट गया है। उसके लटके-झटके जो कभी लाखों में बिकते थे, अब कौड़ियों में बिकने लगे हैं। लेकिन श्रीदेवी इसके बावजूद फिल्में साइन करती चली गयी, इसका कारण यही रहा कि असफल होने के बावजूद श्रीदेवी के टक्कर की कोई अभिनेत्री फिल्म उद्योग में मौजूद न थी। डिंपल कपाड़िया, किमी कातकर, फरहा, अमृता सिंह, मंदाकिनी जैसी अभिनेत्रियों में उससे मुकाबला करने का दमखम न था।

इधर श्रीदेवी का इतना दुर्दिन आ गया कि माधुरी दीक्षित जैसी उपेक्षित हीरोइन को श्रीदेवी के समकक्ष ही नहीं रखा गया, बल्कि पत्र-पत्रिकाओं में माधुरी के पक्ष में एक जोरदार मुहीम चल पड़ी। 'तेजाब' में जिस नाच की वजह से उसका 'क्रेज' बना, उससे सिद्ध हो गया कि अब श्रीदेवी के दिन लद गये और अब माधुरी दीक्षित के पास नंबर वन का खिताब है। माधुरी दीक्षित को श्रीदेवी से भी अच्छी अभिनेत्री बताने के पीछे क्या राज हो सकता है, यह सवाल श्रीदेवी के एक करीबी रिश्तेदार से पूछे जाने पर उसका जवाब था, "फिल्म इंडस्ट्री में मुंह में राम बगल में छुरी वाला चरित्र ज्यादा है। माधुरी दीक्षित को श्रीदेवी से ज्यादा सफल बताने वाले लोग चुपचाप षड्यंत्र चला रहे हैं। सामने यही लोग कहते हैं, श्रीदेवी नंबर एक से लेकर ग्यारह नंबर तक है, तब माधुरी का या किसी और अभिनेत्री का नाम आता है।"

माधुरी दीक्षित जिसके दिमाग आजकल सातवें आसमान पर हैं, से श्रीदेवी का नाम लेने

श्रीदेवी

छाया: नेटवर्क

फिल्मों में हीरो पर दर्शकों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना श्रीदेवी के लटकों-झटकों पर।

पर कहती है, "श्रीदेवी का और मेरा क्या मुकाबला? वह मुझसे कहीं ज्यादा सीनियर और मंजी हुई हीरोइन हैं। उनकी बहुत सी फिल्में हिट हुई हैं, मेरी तो अभी दो ही फिल्में चली हैं 'तेजाब' और 'राम लखन'...।"

यह भी कहा जा रहा है कि माधुरी को श्रीदेवी से श्रेष्ठ सिद्ध करने में जितने लोगों का हाथ है, उनमें निर्माता-निर्देशक सुभाष घई और अभिनेता अनिल कपूर प्रमुख हैं। मगर श्रीदेवी जिन फिल्मों में काम कर रही है, उनके निर्माताओं का कहना है, "श्रीदेवी अपने उसी पहले नंबर की स्थिति में है, जिससे उसे उतारने की कोशिश कई अभिनेत्रियों ने किया, मगर ऐसा हो नहीं पाया। जयाप्रदा, रेखा, डिंपल आज भी पीछे हैं। कुछ ही दिनों में माधुरी को भी पता लग जायेगा कि वह कितना आगे दौड़ सकती है।"

'नगीना' जैसी चमत्कारिक हिट फिल्म बनाने वाले हरमेश मल्होत्रा इसी फिल्म का दूसरा भाग बना रहे हैं—'निगाहें'। 'निगाहें' की कहानी वहां से शुरू होती है, जहां 'नगीना' की कहानी खतम हुई थी। 'नगीना' में हीरो थे ऋषि कपूर और 'निगाहें' में हीरो हैं सनी देवल। इसके निर्माता हरमेश मल्होत्रा का कहना है कि ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में शायद पहली बार हो रहा है, जब एक ही फिल्म का दूसरा भाग पूरी फिल्म की ही तरह बन रहा है। मेरा विश्वास है कि 'निगाहें' दूसरी 'नगीना' साबित होगी और पब्लिक को एक बार फिर श्रीदेवी का लोहा मानना पड़ेगा। आरके स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग अपने अंतिम चरण में थी। संपेरा नृत्य श्रीदेवी पर फिल्माया जा रहा था। अतः वहां जो उससे लंबी बातचीत हुई, उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं:

श्रीदेवी और सनी देवल

छाया: प्रदीप एन राय

'निगाहें' दूसरी 'नगीना' साबित होगी और पब्लिक को एक बार फिर श्रीदेवी का लोहा मानना पड़ेगा।

माया: *आपका नंबर वन का खिताब क्या वाकई माधुरी दीक्षित ने छीन लिया?*

श्रीदेवी: *(हंसी) मेरी आज तक समझ में नहीं आता कि यह नंबर वन और नंबर टू वाली बात है क्या? इसे न तो सरकार देती है, न प्रेसीडेंट आफ इंडिया और न पब्लिक। पहले पता लगाइए यह टायटिल देता कौन है?*

माया: *फिल्म उद्योग के लोग जिनमें निर्माता ज्यादा हैं। अपनी फिल्म की हीरोइन को वह नंबर वन बताते हैं...*

श्रीदेवी: *तब मैं ही क्यों नंबर वन हुई, वह हर ऐक्ट्रेस जो फिल्म की हीरोइन है, नंबर वन कहलायी जानी चाहिए।*

माया: *नहीं, नंबर वन कहलाये जाने का अधिकार उसी अभिनेत्री को है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में हिट हों...*

श्रीदेवी: *मगर मेरी फिल्में पिटी भी हैं, पिटेंगी भी और पिट भी रही हैं।*

माया: *तो इस स्थिति में कैसा महसूस हो रहा है?*

श्रीदेवी: *कुछ भी नहीं। फिल्में वैसे ही मिल रही हैं, जैसी मिलती आयी हैं।*

माया: *और, आप साइन करती आ रही हैं?*

श्रीदेवी: *ना, तब तक नहीं जब तक मुझे फिल्म में अपना रोल कनविंसिंग न लगे।*

माया: *पहले आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हीरोइन का कोई स्कोप नहीं होता...*

श्रीदेवी: *बिलकुल कहा था।*

माया: *लेकिन अब आपने उनके साथ दो फिल्में साइन की हैं।*

श्रीदेवी: *इसलिए कि मुझे उनमें हीरोइन का रोल काफी अच्छा लगा। बतौर हीरोइन काफी कुछ कर दिखाने की गुंजाइश इन पटकथाओं में थी, सो मैंनें काम करने की सहमति दे दी।*

माया: *फिल्म साइन करते वक्त क्या आप इस बात पर भी ध्यान देती हैं कि हीरो कौन है या किसे होना चाहिए।*

श्रीदेवी: *ना, मैं सिर्फ अपने रोल पर ध्यान देती हूं।*

माया: *रोल अच्छा होने पर भी फिल्म न चले तो...?*

श्रीदेवी: *न चले। मैं अपना काम ईमानदारी से निभाती हूं। आज तक मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरी कौन सी पिक्चर चली और कौन सी नहीं चली? मेरा काम अच्छा है, इसीलिए इंडस्ट्री में टिकी हुई हूं। जिस दिन ऐसा नहीं होगा, अपने आप प्रपोजल्स आने बंद हो जायेंगे। और हां, मुझे लोग नंबर वन कहते रहे, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, नंबर टेन भी कहें, तो भी फर्क नहीं पड़ता...।*

छाया: डीआर यादव

माया: *बीच में आपकी राजनीति में जाने की बात थी?*

श्रीदेवी: *नैवर, मैं जन्मतः अभिनेत्री हूं। वही रहूंगी। फिल्मों और स्टूडियो के अलावा जो दुनिया है, वहां के जो काम हैं, वहीं के लोग उसे अच्छी तरह निभा सकते हैं। पालिटिक्स में बड़े-बड़े नेता हैं, मैं उनके काम में क्यों दखल दूं? मैं अभिनेत्री ही भली।*

माया: *शादी के बारे में कुछ सोचा?*

श्रीदेवी: *(हंसी) यह सोचना मेरा काम नहीं है। मेरे माता-पिता के सोचने की बात है।*

माया: *तो वे सोच रहे हैं?*

श्रीदेवी: *(हंसी) कौन मां-बाप ऐसे हैं, जो अपनी बेटी की शादी की बात नहीं सोचते?*

—हरीश तिवारी

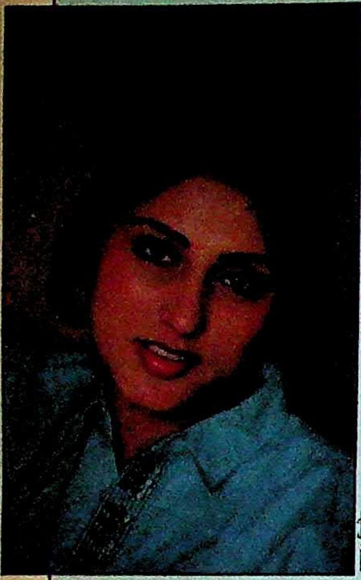

छाया : किशोर

महाभारत की द्रौपदी : रूपा गांगुली

द्रौपदी का जलवा

रूपा गांगुली के लिए जैसे समूचा परिदृश्य ही बदल गया है। इसके पहले जब वह बंबई आती थी, तो पड़ोसवाले भी उस पर नजर नहीं डालते थे। रवींद्रनाथ टैगोर की कहानियों पर बनी टेलीफिल्मों में जब उसने काम किया, तब भी कोई नहीं उसे पहचानता था और न ही तब जब 'गणदेवता' में वह दुर्गा की सेक्सी-ग्लैमरस भूमिका निभा रही थी। लेकिन बीआर चोपड़ा ने उसे 'महाभारत' के लिए द्रौपदी क्या चुना कि रूपा रातोरात हंगामे का विषय बन गयी। फिल्मी पार्टियों, मुहूर्तों में उसकी मौजूदगी जरूरी मानी जाने लगी, बड़े-बड़े सितारे उसके साथ अपने चित्र खिंचवाने के लिए लालायित हो उठे। पत्रकारों-छायाकारों के दस्तक से परेशान होकर उसे गुप्त रूप से एक होटल में टिका दिया गया और कड़े 'इस्कोर्ट' में उसे होटल से शूटिंग-लोकेशन पर ले जाया जाने लगा।

द्रौपदी के चुनाव में बीआर चोपड़ा को जितनी परेशानी हुई उतनी तो उन्हें 'महाभारत' को ओके कराने में मंडीहाउस से भी नहीं हुई। उन्होंने जूही चावला सहित जिस-जिसको द्रौपदी की भूमिका के लिए फाइनल किया, उसने अचानक मिली लोकप्रियता का फायदा उठाकर फिल्मों की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। एक बार उनकी निगाह सुजाता मेहता पर भी गड़ी कि श्याम बेनेगल ने द्रौपदी की भूमिका उसे 'भारत एक खोज' में थमा दी। सावधान चोपड़ा ने २९ द्रौपदियों में से अंतिम द्रौपदी रूपा को चुनते ही शूटिंग शुरू कर दी। अब यह बात दूसरी है कि दीपा साही, किरण जुनेजा, जूही चावला की तरह रूपा ने भी आगे सिर्फ फिल्मों में ही काम करने का निर्णय किया है।

'शेष' का साथ

'बुनियाद' सीरियल के दौरान हवेलीराम (आलोकनाथ) तथा लाजोजी (अनीता कंवर) को मिली अकूत लोकप्रियता से लगा था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी के स्टारडम पर कब्जा कर लिया है। फिल्म निर्माताओं की भीड़ भी कुछ इस कदर उनके इर्द-गिर्द इकट्ठी होने लगी थी कि उन्हें भी इसका मुगालता हो गया था, लेकिन सीरियल खतम होने के बाद यही भीड़ जब उन्हें अकेला छोड़ गयी, तो उन्हें अपनी असलियत का अहसास हुआ। इन 'सुपर सितारों' का जब १९८८ में कोई नामलेवा भी नहीं रहा, तो उनकी मदद के लिए आगे आये 'बुनियाद' के कार्यकारी निर्माता अमित खन्ना जिन्होंने अपनी नयी फिल्म 'शेष' में दोनों को अनुबंधित कर लिया।

आलोकनाथ और अनीता कंवर फिल्म 'शेष' में

आलोकनाथ तथा अनीता कंवर ने 'शेष' में प्रभावशाली अभिनय किया है और इसका असर उनके कैरियर पर अभी से दिखलायी पड़ने लगा है। उन्हें उम्मीद है कि 'शेष' के प्रदर्शित होते ही वे स्टारडम भले न हासिल कर पायें, लेकिन संजीव कुमार तथा गुरुदत्त की श्रेणी के कलाकारों में उनकी गिनती जरूर होने लगेगी।

जानी लिवर की सांसत

खुद को 'नकलचियों (मिमिक्री) का बादशाह' माननेवाले जानी लिवर इस बार खुद के बनाये जाल में फंस गये हैं। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक का नकल कर चवन्नियां और बाल दर्शकों के ठहाके बटोरते-बटोरते प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नकल उतार कर वे कई बार सरकारी अफसरों की जान सांसत में डाल चुके हैं।

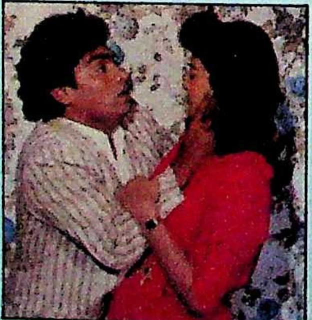

जानी लिवर और जैक्वलीन. 'कांटा' में

पिछले दिनों फरार माफिया डान दाऊद द्वारा अपने भतीजे इब्राहीम के जन्मदिन पर दुबई के एक पंचसितारा होटल में वे इस कदर जोश में आये कि राष्ट्रगीत की ही नकल शुरू कर दी। उन्होंने विशेष अंदाज में राष्ट्रगीत में 'यमुना-गंगा' शब्द आते ही तैरने, 'पंजाब सिंध' पर भांगड़ा और 'गुजरात-मराठा' पर तंबाकू खाने की जोरदार एक्टिंग कर डाली। कानून के पहरेदारों का यह कहना है कि जानी लिवर ने ऐसा कर 'नेम्स एंड एंबलम ऐक्ट' के हिसाब से दंडनीय अपराध किया है।

संजय दत्त की पिस्तौल

संजय दत्त और पिस्तौल के बीच एक तरह से ३६ का रिश्ता है, लेकिन उनकी लत है कि छुड़ाये नहीं छूटती! वे बिना पिस्तौल के रह भी नहीं सकते और पिस्तौल है कि उन्हें विवाद में घसीटे बगैर नहीं छोड़ती। जबकि उनकी मम्मी (स्व० नर्गिस) पिस्तौल देखकर थरथराने लगती थीं, बेटे संजय को निजी जिंदगी में उंगलियों पर पिस्तौल घुमाने की आदत है। वे किसी तरह ड्रग्ज लेने की आदत से मुक्ति तो पा गये हैं, लेकिन पिस्तौल-लत ने उन्हें पिछले दिनों लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक तरह से फंसा ही दिया था।

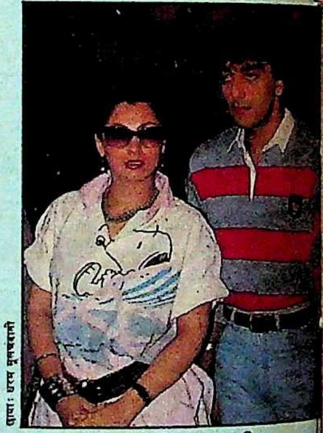

छाया : परम मुखर्जी

संजय दत्त और डिंपल कपाड़िया

भला हो बंबई कस्टम अधिकारियों का, जिन्होंने दौड़-धूप कर उन्हें इस मुसीबत से बचा तो लिया है, लेकिन संजय दत्त इस पिस्तौल-लत से कब छुटकारा पायेंगे, वे खुद नहीं जानते!

—अखबारी लाल

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए [illegible] प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

आओ मिलकर हम 'घर-घर' खेलें!

Practical guide to
home landscaping

जब जीवन भर की पूंजी लगायेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिये अपनी निशानी भी तो छोड़ कर जायेंगे।

जी हां! आखिर जीवन भर की पूंजी लगाकर जब अपना घर बनायेंगे तो किसी भी चीज़ में समझौते का सवाल ही नहीं उठता। खासकर सीमेन्ट का चुनाव तो बहुत ही सोच समझकर कीजियेगा।

फिर सबसे बेहतर सीमेन्ट की सही पहचान तो किसी अच्छे बिल्डर को ही हो सकती है, है ना? तो भारत के नं. 1 बिल्डर जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के वर्षों के अनुभव का फायदा अब आप भी उठाइये। जिस सीमेन्ट से वे बड़े-बड़े पुल और बांध देश-विदेश में बनाते हैं, उसी भरोसेमन्द सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट से आप भी अपना घर बनवाइये।

सीमेन्ट की क्वालिटी का मापदण्ड हमेशा उसमें उपयोग किये गये चूना-पत्थर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इसीलिये सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट का कारखाना देश के सबसे बेहतरीन चूना-पत्थर की खदानों में पास स्थित है। साथ ही साथ सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट अत्याधुनिक कम्प्यूटर युक्त तकनीक से बनाया जाता है।

तभी तो सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट में है बेजोड़ पकड़, लाजवाब मजबूती और बेमिसाल भरोसा।

जब भारत के नं. 1 बिल्डर के अनुभवों से बना सीमेन्ट उपलब्ध है, तो फिर भला किसी और सीमेन्ट को क्यों खरीदें?

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट : इसे नाम से मांगिये।

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट की गारंटी

- तुरन्त मज़बूत पकड़
- 28 दिनों के बदले सिर्फ 3 दिनों में 330 kg/cm² की कम्प्रेसिव मज़बूती।
- हर बोरी में पूरा वज़न – पूरे 50 किलो।

GUARANTEED QUALITY

मजबूत रहे यह बंधन-जीवनभर

सुपरप्लस
जेपी
सीमेन्ट

मास्टर बिल्डर

जयप्रकाश इन्डस्ट्रीज़ का एक उत्कृष्ट उत्पादन

LINTAS (DELHI) JI 58 2621 HI

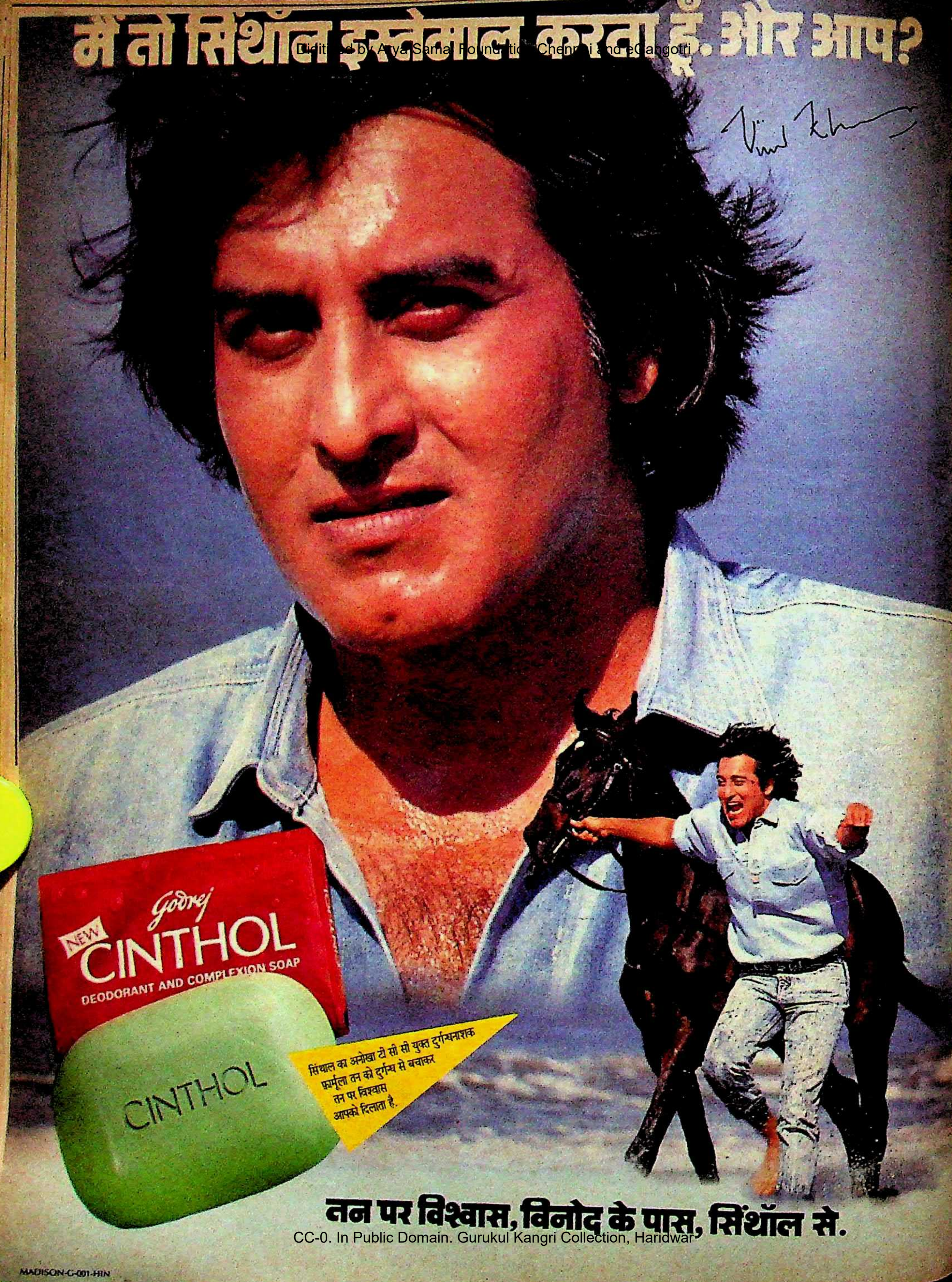
मैं तो सिंथॉल इस्तेमाल करता हूँ. और आप?
Godrej
NEW
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
CINTHOL
सिंथाल का अनोखा टी सी सी युक्त दुर्गंधनाशक फ़ार्मूला तन को दुर्गंध से बचाकर तन पर विश्वास आपको दिलाता है.
तन पर विश्वास, विनोद के पास, सिंथॉल से.
MADISON-C-001-HIN

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका
माया
३० अप्रैल, १९८९
वर्ष ६०, अंक ८

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

• प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७०३ टेलेक्स: ०५४०२८०, • दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन प्वाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९६०३५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezpur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

२९
आवरण कथा

बोफोर्स विवाद के फंदे से तो अभी मुक्ति मिली भी नहीं थी कि ठक्कर आयोग का फंदा सरकार के गले में और पड़ गया है। इस रिपोर्ट को लीक किसने किया? इसे अचानक पेश करने के लिए राजीव गांधी को क्यों बाध्य होना पड़ा? ठक्कर को किस आधार पर यह शक हुआ कि धवन श्रीमती गांधी की हत्या में मददगार सिद्ध हुए? चुनाव वर्ष में इस रिपोर्ट के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे?

विशेष रिपोर्ट
जनता दल के अध्यक्ष वीपी सिंह और वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर का द्वंद्व क्या मोड़ ले सकता है? १८

खोजखबर
चुरहट लाटरी कांड के बाद मध्य प्रदेश में गहराये इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट लाटरी विवाद की छानबीन ४६

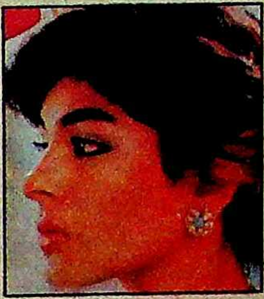

प्रसंगवश
'मिस इंडिया' पामेला सिंह ने अपने रूप के जरिये ऐसा क्या कहर ढाया कि उसने ब्रिटेन की सरकार को संकट में डाल दिया? ६६

पंजाब
केंद्र सरकार की नयी पहल के बाद अकाली दल के गुटों की एकता का प्रयास विफल क्यों हुआ? २५

विवाद
उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच १९२६ से चला आ रहा विवाद अचानक हिंसक क्यों बन गया? ६२

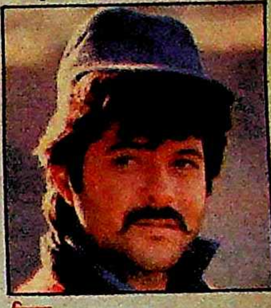

फिल्म
जिस तरह अनिल कपूर की फिल्में हिट हो रही हैं, क्या उससे वह अमिताभ बच्चन से आगे निकल जायेगा? ८३

दिल्ली दरबार: आजाद कर दो ठक्कर को! १०
फोटोफीचर १३
देश: माकपा माकपा की राह पर २३
स्त्री: पामेला की पगली यात्रा ४४
यादें: चोटी पर पहुंचने में बहुगुणा माहिर थे: पीडी टंडन ५४
उत्तर प्रदेश: लखनऊ का गुस्सा मुरादाबाद में फटा ५७
राजस्थान: आवासन मंडल: धांधली और अव्यवस्था के घेरे में ७१
मध्यप्रदेश: खनिज निगम के प्रबंध संचालक क्यों हटाये गये? ७५
बिहार: तारिक अनवर ने मंत्री पद की कुरसी क्यों ठुकरायी थी? ७७
दूरदर्शन: कक्काजी कहिन: छुटभैये नेताओं की असली तस्वीर है? ८१
विवाद: हिंसा की राजनीति और हाजी मस्तान ९०
फैशन: रंग-बिरंगी कमीजों की बाढ़ ९४
परदे के पीछे ९६

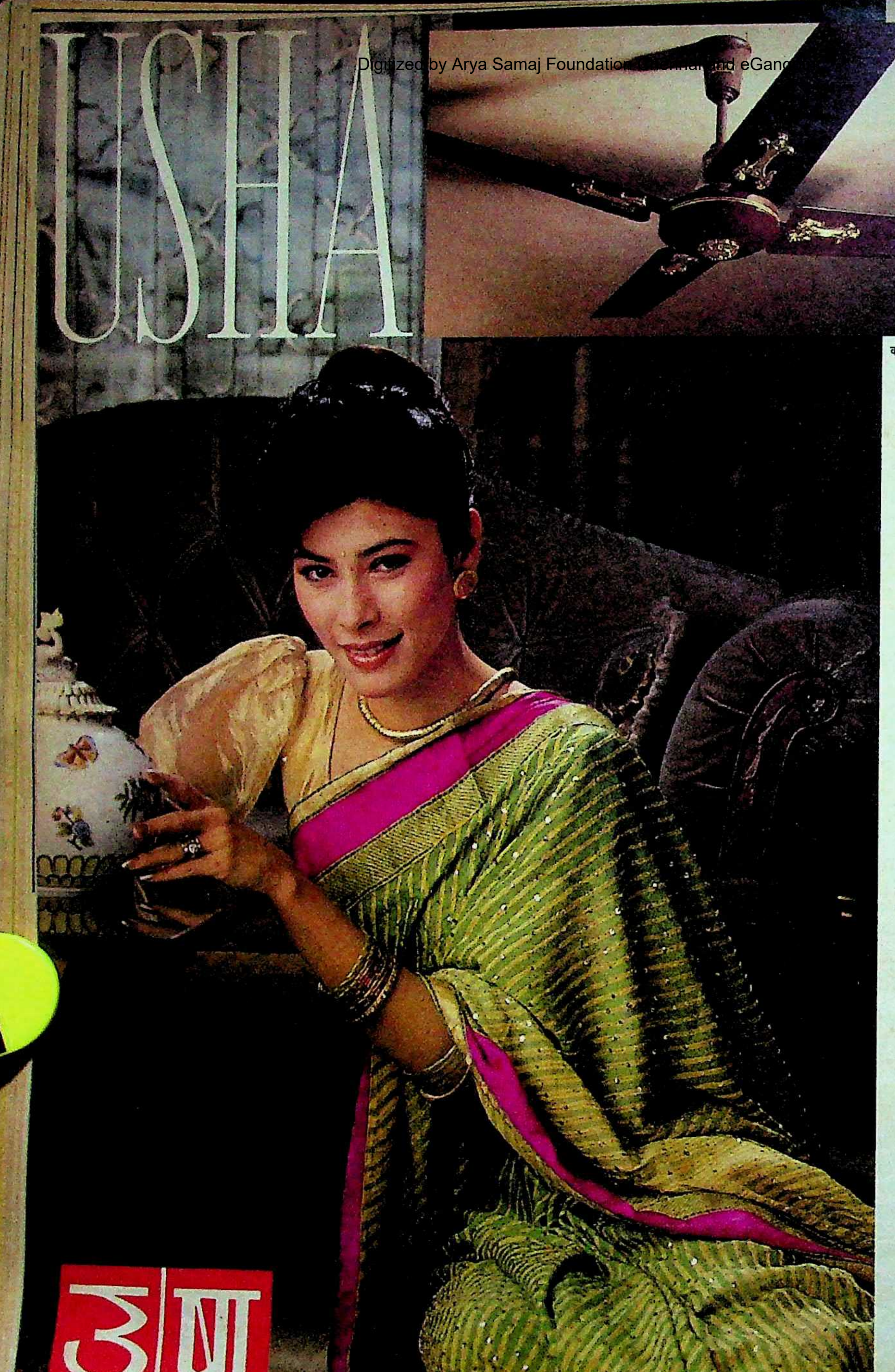

कोहिनूर सुपर डीलक्स 4-ब्लेड

उषा का अंदाज़!

भूरे रंग में सुनहरी सज-धज।
सुंदर रूप, उत्तम तकनीक। बेहतरीन
एयरोडायनेमिक्स और
डबल बॉल बेयरिंग-युक्त।
उषा की 40 वर्षों से अधिक की
उत्कृष्ट तकनीक से रचा।

आपका अंदाज़!

आज 2.73 करोड़ से भी अधिक
उषा पंखों के संतुष्ट
ख़रीदार भारत में और विश्व के
60 देशों में फैले हैं।
उषा पंखे–सीलिंग, टेबल,
पेडेस्टल, वॉल, कैबिन और
एग्ज़ॉस्ट पंखों की
विस्तृत रेंज में।
इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
को भरोसा है उषा पर।

भारत का सर्वाधिक बिकने वाला पंखा

माया
अर्जुन सिंह का जवाबी हमला

अर्जुन सिंह का जवाबी हमला

‘माया’ का १५ अप्रैल का अंक मिला। आवरण कथा ‘अर्जुन सिंह का जवाबी हमला’ देखा। पूरी कथा से चारचश्म होने के बाद यह लगा कि अर्जुन सिंह को हटाने की तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। वैसे भी इंदिरा गांधी से ही यह परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा, तभी उसके पंख कुतरने की व्यवस्था कर दी गयी, वरना भ्रष्टाचार के आरोप लगना तो नेताओं पर आम बात हो गयी है। वैसे भी ज़ब से बोफोर्स की धूम मची है, तब से लगता है कि भ्रष्टाचार भी नेताओं की काबिलीयतों में एक जरूरी खासियत हो गयी है। चरित्र के मामले में तो नेताओं को पहले से ही छूट मिली हुई है। लेकिन अर्जुन सिंह की यह बात कि मैं अभी भी राजीव गांधी को ही अपना सब कुछ मानता-जानता हूं, समझ में नहीं आयी। इतने तिरस्कार के बाद भी यदि अर्जुन सिंह राजीवजी को अपना सब कुछ मानते हैं, तो साफ है कि निकट भविष्य में ही वे दिल्ली में पुनः नमूदार होंगे, इसमें शक नहीं।—**कुमार शंकर, १८ लीचू बागानलेन, कलकत्ता**

धवन की वापसी

‘माया’ (३१ मार्च, १९८९) की आवरण कथा में तीन लेख पढ़े। धवन की वापसी से संबंधित जुड़े मुद्दों पर आपने इतना बारीक विवेचन प्रस्तुत किया है कि स्वयं धवन भी अपने चरित्र के कई पहलुओं से जुड़ी प्रकाशित पंक्तियों को पढ़कर आश्चर्यचकित रह जायें। बहरहाल, ‘धवन को क्या करना है तथा क्यों निकाला गया था’ जैसे विषयों पर उत्कृष्ट सामग्री पढ़ने के बाद सारी तस्वीर सिनेमा की रील की तरह आंखों के आगे घूम जाती है। जो भी हो आगामी कार्यकलापों में अनूठे व्यक्तित्व की ही झलक मिलेगी। परंतु क्या वे सफल होंगे? यह प्रश्न अभी भविष्य के गर्भ में है।—**आलोक कुमार झा, बीके नगर, भागलपुर**

घटकवाद की घुटन

‘माया’ (३१ मार्च ’८९) में जनता-दल पर प्रस्तुत रपट ‘घटकवाद की घुटन’ पढ़कर मुझे स्थानीय एक दैनिक पत्र के संपादकीय की यह कड़ी याद आ गयी ‘सत्ताधारी दल का विकल्प बनने का मंसूबा रखना एक बात है और उसकी वास्तविक योग्यता प्राप्त करना दूसरी बात है।’ जो कुछ भी इस दल में घट रहा है, उसे देखते हुए, तो यह टिप्पणी इन लोगों पर व्यंग्य-बाण का प्रहार ही करेगी। शायद इसीलिए विकल्परूपी एक संगठन बनाकर भी ये लोग ‘अपनी कुरसी-अपनी पार्टी’ के अस्तित्व के लिए जिस तरह जूतम पैजार कर रहे है, वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इन्हें ‘जोकर दल’ का नाम देकर हास्य का पात्र भी बना रही है। —**ताराचंद ‘देव’ गाडेगावालिया, हरिद्वार**

आरएसएस के खतरनाक तेवर

‘माया’ (३१ मार्च) में ‘हिंदू संगम’ की रिपोर्ट पढ़ी। काफी हद तक ठीक थी। किंतु इस रिपोर्ट में आरएसएस द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु ‘सांप्रदायिक फसल’ शब्द एकदम नागवार लगा। यदि कोई संगठन देश के ८७ प्रतिशत लोगों को संगठित करने की कोशिश करता है, तो उसे सांप्रदायिक करार दिया जा रहा है।

हिंदू शब्द तो अपने आप में मानवता, प्रेम एवं विश्व बंधुत्व का परिचायक है। लेखकों ने हिंदुओं को संगठित करने को भी एक ‘खतरनाक प्रवृत्ति’ माना है, जो सर्वथा अनुचित है। यदि राष्ट्र-हित, समाज-हित एवं मानव हित में कोई संगठन बनता है, तो यह स्वागतयोग्य है। वैसे भी संगठन तो प्रकृति के अनुकूल बनने हेतु, बेहतर तरीके से जीने हेतु मानव की पहली आवश्यकता है।—**रवींद्र कुमार, सरदारशहर, चूरू, राजस्थान**

भोपाल गैस कांड : समझौता या सौदा ?

‘माया’ के ३१ मार्च के अंक में ‘भोपाल गैस कांड : समझौता या सौदा ?’ पढ़ा। सचमुच प्रधानमंत्री ने आगामी चुनाव को देखते हुए ही मात्र ७१५ करोड़ रुपयों पर समझौता कर लिया चाहे पीड़ितों को कितने ही कम पैसे मिलें।—**भरत जैन, शास्त्री वार्ड, सागर, मप्र**

रुश्दी की खता क्या है ?

‘माया’ के ३१ मार्च वाले अंक में ‘रुश्दी की खता क्या है ?’ पढ़ा। साहित्य के दृष्टिकोण से जिस किताब की हैसियत जुगनू सरीखी भी नहीं है, उसे किताब पर लगे प्रतिबंध, खुमैनी के फतवे, राजनयिक संबंध तोड़ने की कार्रवाई तथा दंगे और प्रदर्शन ने सोडियम वेपर लैंप बना दिया।

‘द सेटेनिक वर्सेज’ अगर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का बेहया प्रदर्शन है, तो खुमैनी का फतवा धार्मिक दिवालियेपन का सुबूत। मुसलमान भाइयों को यह सोचना चाहिए था कि आसमान की ओर मुंह करके थूकने से आसमान गंदा नहीं होता, बल्कि वह थूक उसी व्यक्ति के मुंह को गंदा करता है। पैगंबर की सीख इतनी हलकी नहीं है कि एक तथाकथित पुस्तक की चंद पंक्तियां उसे बौनी बना दें।—**राजीव लोचन मंटू, घोसैठ, मुंगेर, बिहार**

‘माया’ के ३१ मार्च की रपट ‘रुश्दी की किताब पर दुनिया भर में हंगामा’ पढ़कर इस बहुचर्चित प्रकरण के विविध तथ्यों से अवगत हुआ। निश्चय ही अयातुल्ला खुमैनी द्वारा सलमान रुश्दी की औपन्यासिक कृति ‘द सेटेनिक वर्सेज’ में लिखित अनुचित आक्षेपों का तर्कपूर्ण विरोध न कर उनकी हत्या का आदेश देना उनकी संकीर्ण धार्मिक कट्टरता का प्रतीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन और विश्व मानवता की दृष्टि से अनुचित ही प्रतीत होता है।—**चंद्रकांत यादव, चांदीतारा, वाराणसी।**

ऊंट किस करवट बैठेगा ?

‘माया’ (३१ मार्च) में प्रसिद्ध खेल समीक्षक रवि चतुर्वेदी का लेख ‘ऊंट किस करवट बैठेगा ?’ बेहद रोचक व विचारोत्तेजक था। भारतीय टीम एकदिवसीय शृंखला हार चुकी है। यदि एकदिवसीय मैचों को देखा जाये, तो नजर आता है कि नये खिलाड़ियों में अजय शर्मा के अतिरिक्त किसी का भी प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। पुराने खिलाड़ियों में केवल कपिल देव ही भरोसे के साबित हो रहे हैं। स्वयं कप्तान वेंगसरकर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। धीरे-धीरे मोहिंदर की कमी स्पष्ट नजर आ रही है। जिस समय यह टीम चुनी गयी थी, उस समय बड़ी संतुलित नजर आ रही थी। लेकिन चयनकर्ता भूल गये कि नये खिलाड़ियों का परीक्षण घरेलू शृंखला में किया जाता है न कि वेस्ट इंडीज के साथ उसी की भूमि पर। इससे नये खिलाड़ियों का भविष्य भी चौपट होता है तथा टीम भी हारती है।—**हर्ष कुमार, देवपुरम्, मुजफ्फर-नगर, उप्र**

आवश्यकता है साफ नजरिये की

‘माया’ (३१ मार्च अंक) में ‘स्त्री’ स्तंभ के अंतर्गत ‘वसंत साठे उवाच’ में श्रीमती ममता कालिया ने ‘भ्रूण परिक्षण’ के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे भावुकतापूर्ण हैं। इस विषय में सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए जैसे—पहले ‘गर्भ’ में यदि लड़की है, तो उसे अंदर ही नष्ट करना उचित नहीं है, किंतु यदि दो या तीनों संतानें पुत्रियां ही हैं, तो फिर कोई क्यों और बेटी चाहे? अतः बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इस प्रकार की भावनाओं में पाठकों को बहाने की आवश्यकता नहीं। सरकार भी आज स्त्री के नाम पर पुरुषों के अधिकार छीन रही है, जो अनुचित है।—**मनोज कुमार श्रीवास्तव, विदिशा, मप्र०**

मैं लोगों की बातों की परवाह नहीं करता

‘महाभारत का महाभारत’ लेख के साथ पटकथा व संवाद-लेखक डा० राही मासूम रज़ा को जान से मार डालने की धमकी वाली बात पढ़कर बेहद दुख हुआ। राष्ट्रीयतावादी शक्तियों को नष्ट कर देने का इससे खुला चैलेंज और क्या हो सकता है। कतिपय दिग्भ्रमित मानसिकता के प्रतिक्रियावादी लोगों के राष्ट्रहंता विचारों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रखर विरोध अवश्य ही होना चाहिए। डा० रज़ा का यह कथन विचारणीय है

कि यदि स्कालरों ने गलतियां न की होतीं, तो आज हम उस नरक से न गुजर रहे होते, जिस नरक से गुजर रहे हैं।—**गणेश कुमार 'पथिक' आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, सिरौली, बरेली**

स्वामी को कथित दस्तावेज किसने दिये?

'माया' का १५ मार्च, १९८९ वाला अंक मिला। 'स्वामी को कथित दस्तावेज किसने दिये?' लेख के अंतर्गत सुधा भाटिया ने स्पष्ट और बेबाक आकलन किया है। स्वामी को कथित दस्तावेज चाहे कांग्रेस से मिले हों, चाहे विपक्ष से, स्वामी की हैसियत मात्र कठपुतली-सी है। पब्लिसिटी पाने के लिए स्वामी समय-समय पर शिगूफा छोड़ते रहे हैं।—**प्रेमनाथ, गंज, अजमेर**

शंकराचार्यों में विवाद क्यों है?

आपकी लोकप्रिय पत्रिका 'माया' के १५ मार्च '८९ के अंक में 'शंकराचार्यों में विवाद क्यों है?' शीर्षक लेख पढ़ने को मिला। इस क्रम में स्वयं ज्योतिमठ (अब वर्तमान जोशीमठ) का स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं भी जनता के सम्मुख कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। स्वामी स्वरूपानंदजी सरस्वती ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य कदापि नहीं हैं। वे एवं उनके गुरुभाई श्री कृष्णवोधाश्रमजी ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के उत्तराधिकार के लिए भारत के कई न्यायालयों में लड़े, लेकिन असफल रहे। अब वर्तमान में ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती हैं न कि स्वरूपानंदजी। स्वामी स्वरूपानंदजी से यह निवेदन है कि कृपया इसी पत्रिका के माध्यम से जनता को बतलाने की कृपा करें कि क्या आप जोशीमठ में एक अतिरिक्त मठ की स्थापना करने आये थे या आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने? क्या उक्त अनुसंधान केंद्र (जिसमें कि आपने आम जनता को आश्वासन दिया था कि यहां के समस्त बेरोजगार युवकों को इसमें प्रशिक्षण देकर उनको बेरोजगारी से मुक्ति दिलवायी जायेगी) के उक्त भवन का शिलान्यास तत्कालीन गढ़वाल के सांसद माननीय श्री परिपूर्णानंद पैन्यूली द्वारा नहीं किया गया था? कृपया श्री स्वरूपानंदजी यह भी स्पष्ट करें कि जिस गुफा का नाम उन्होंने त्रोटकाचार्य गुफा रख दिया है, क्या वह वास्तव में सही गुफा है? क्या वे इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं,

—**लक्ष्मी लाल शाह, नगरपालिका, जोशीमठ**

जननेता चंद्रशेखर का सच

विगत अनेक दशकों से 'माया' ने सदैव देश के हित को ध्यान में रखते हुए निर्भय पत्रकारिता की अपनी परंपरा को कायम रखकर १५ मार्च '८९ के अंक में जननेता चंद्रशेखर का सच छाप कर एक नया तहलका मचाया है। प्रकाशित साक्षात्कार में चंद्रशेखर का यह बयान अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 'भारत का भविष्य चिंतनीय नहीं है, क्योंकि इतिहास बदलना हर मामूली आदमी के बस का काम नहीं है।' मैं चंद्रशेखर के इस सच को दूसरा ऐतिहासिक सच मानता हूं। पहला वह था, जब उन्होंने इंदिराजी से कहा था, "जयप्रकाशजी से समझौता कर लीजिये वरना कांग्रेस के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे।" और हमने देखा था कि उनकी चेतावनी सत्य हुई, तो क्या इस बार पुनः सच बोलकर चंद्रशेखर ने देश के कोरे हंगामा मचाऊ बौने नेताओं को सावधान किया है।

—**मुकुंददास माहेश्वरी, डीबी बल्लभदास प्लेस, जबलपुर, मप्र०**

◆ खयालात

वीपी सिंह तथा अन्य नेताओं को पार्टी से हटाकर, नेतृत्व ने कांग्रेस-इ सांसदों के खिलाफ इस तरह मोर्चाबंदी कर रखी है कि उनके लिए विकल्प की भाषा में सोचना भी घातक बन गया है।—**असंतुष्ट इंका सांसद चिमनभाई मेहता, सांसदों के नाम पत्र में**

राष्ट्रीय मोर्चा पंजाब समस्या के हल को कितनी प्राथमिकता देता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसके ७१ सूत्रीय कार्यक्रम में पंजाब ६७वें नंबर पर है।—**राजीव गांधी, दिल्ली में**

राजीव गांधी, उनकी पार्टी और सरकार द्वारा पंजाब समस्या के हल को दी गयी प्राथमिकता के नतीजे तो देश देख-भुगत चुका, अब एक मौका राष्ट्रीय मोर्चे को भी देकर देखना चाहता है, तो राजीवजी संतुलन खोते जा रहे हैं।—**प्रो० मधु दंडवते, दिल्ली में**

प्रधानमंत्री के फैसले (बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सत्येंद्र नारायण सिंह की नियुक्ति) के लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, उसने पार्टी, राज्य और राष्ट्र के लिए जातिवाद का जहरीला बीज बोकर अच्छा नहीं किया है।—**सांसद अब्दुल गफूर, पटना में**

इंदुभाई पटेल के नेतृत्ववाली जनता पार्टी का कांग्रेस-इ के साथ गुपचुप विलय-समझौता हो गया है, यह विलय चुनाव के पहले भी हो सकता है और या बाद में भी।—**रामकृष्ण हेगड़े, बंगलौर (प्रेस कांफ्रेंस) में**

राजीव गांधी

देश के लोग खूब समझते हैं उस खेल (ठक्कर रिपोर्ट आम करने के हठ) को, जो विपक्ष, 'येन केन प्रकारेण' सत्ता में आने के लिए, खेल रहा है।—**संसदीय कार्यमंत्री हरिकिशन लाल भगत, लोकसभा में**

अब, जबकि कोई बाहरी साक्षी नहीं रह गया है (विदेशी पत्रकार हटा दिये गये हैं), चीनियों को खुली छूट मिल गयी है और मुझे डर है कि तिब्बत कत्लगाह जैसी जगह बन जायेगा।—**दलाई लामा, न्यूयार्क (टाइम) में**

इंकावालों का खयाल है कि उनकी पार्टी गंगा के समान है और पाक या नापाक, जो भी (गुट या दल) उसमें अपना विलय करता है, वह रातोरात पवित्र हो जाता है।—**अटलबिहारी वाजपेयी, 'संडे' में**

पामेला बोर्डेस

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आगामी चुनाव में सत्ता से राजीव गांधी के हटने के आसार से नाखुश है।—**लालकृष्ण आडवाणी, दिल्ली में**

कैसा माफिया? कौन-सा माफिया? मैं पसंद नहीं करता इसे, 'माफिया' कोई अच्छा शब्द नहीं है।—**बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, प्रेस कांफ्रेंस में**

विपक्ष के बारे में मेरी अवधारणा यह नहीं है कि वीपी सिंह को सिर्फ बोफोर्स-रहित राजीव होना चाहिए।—**राम जेठमलानी, 'इंडिया टुडे' में**

इनके बारे में अखबारों ने जितना कुछ कहा है, उसमें बहुत-सी बातें अतिरंजित हैं, एक इंसान के रूप में राजीव (गांधी) को उन्होंने गलत नहीं पाया है।—**फिल्मनिर्माता सिम्मी गरेवाल, 'एशिया वीक' में**

मैं पूरी रात साथ-साथ रहा, पर मुझे नहीं लगता कि मिस (पामेला) बोर्डेस से मैंने दो शब्द से अधिक कहे हों।—**ब्रिटिश सांसद डेविड इवांस, 'टुडे' में**

अगर मैं मुंह खोल दूंगी, तो ब्रिटिश सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह-बिखर जायेगी।—**पामेला सिंह बोर्डेस, 'इंडिपेंडेंट' में**

अगर हम (मिजोनेशनल फ्रंट) फिर कभी हथियार उठायेंगे, तो भारत की रक्षा के लिए ही ऐसा करेंगे। —**लालडेंगा, 'टेलीग्राफ' में**

सब जानते हैं कि मैं उड़ीसा की सबसे सख्तजान औरत हूं।—**नंदिनी सत्पथी**

उन्हें (न्यायमूर्ति ठक्कर) अपनी रिपोर्ट का नाम रखना चाहिए था, 'धवन को फांसी कैसे चढ़ायें?'

— **आरके धवन**

वे * (कलकत्ता तैराकी क्लब) शेरवानी पहनने की इजाजत नहीं देते, पर उत्तेजना जगानेवाली हर तरह की पोशाक पहनने की छूट देते हैं। ऐसी मगरूरी तो नहीं चलने दी जानी चाहिए।—**न्यायाधीश बीपी बनर्जी, कलकत्ता में**

क्या पामेला कुंभ में आयी थी ?

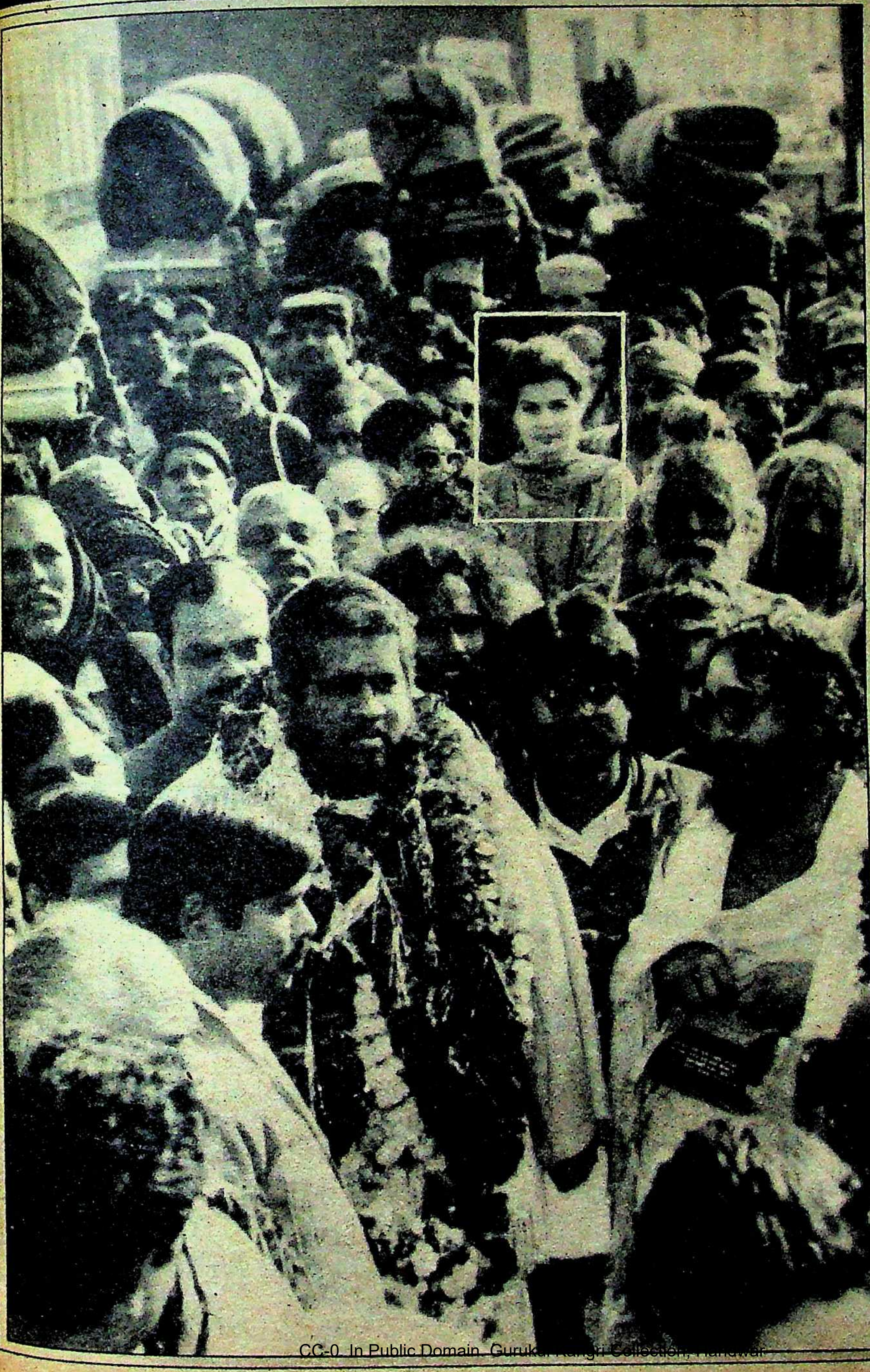

इस बार इलाहाबाद महाकुंभ में जब पहली दफा बहुचर्चित तांत्रिक चंद्रास्वामी पधारे, तो उनके साथ एक रूपसी भी थी, जिसको वे 'मिस यूनिवर्स' बता रहे थे। उनके शिविर में यह 'मिस यूनिवर्स' ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। स्वामी इस 'मिस यूनिवर्स' का नाम से परिचय करवाने और उसके साथ अपना फोटो खिचवाने से कतराते रहे। इस युवती का चेहरा हूबहू पामेला बोर्डेस से मिलता था। क्या स्वामी इसीलिए उसके साथ फोटो खिचवाना नहीं चाहते थे ? यदि वह युवती पामेला थी, तो कुंभ में किस लिए आयी थी—स्नान के लिए... सैर-सपाटे के लिए, या फिर और कोई मिशन था ? बहरहाल इलाहाबाद स्टेशन पर स्वामी के साथ अनूप मेहरोत्रा का खींचा गया चित्र प्रकाशित किया जा रहा है। पाठक स्वयं निर्णय कर लें कि वह पामेला थी या और कोई ?

रम ही फौजियों की हमदम

फिरंगी सरकार के जमाने में ही हमारे देश की सशस्त्र सेना के जवानों व अफसरों के साथ शराब के जो 'जीवन साथी' जैसे रिश्ते कायम हुए, वे न सिर्फ आज भी बरकरार हैं, बल्कि उत्तरोत्तर प्रगाढ़तर होते जा रहे हैं। हालांकि इसके कुप्रभाव भी सामने आये हैं और आयेंगे। हां, आपकी यह जिज्ञासा, कि हमारे फौजी भाई शराब की किन किस्मों से शौक फरमाते हैं, तो आप सीधे रक्षामंत्री या रक्षा राज्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं। गत ७ मार्च को रक्षा राज्यमंत्री चिंतामणि पाणिग्रही ने राज्यसभा में एक ऐसे ही सवाल के जवाब में विधिवत वक्तव्य दिया। इसके साथ ही उन्होंने सेना को मुहैया की जानेवाली किस्म-किस्म की शराबों के आंकड़े भी जारी कर दिये। यदि पाणिग्रही के इस बयान के संकेत को समझने और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाये, तो पकड़ में आनेवाला पहला सच होगा कि १९८८ में भी 'रम' हमारे फौजी भाइयों की 'अव्वल हमदम' बनी रही।

आपकी यह जिज्ञासा कि हमारे फौजी भाई शराब की किन किस्मों से शौक फरमाते हैं, तो आप सीधे रक्षा राज्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं।

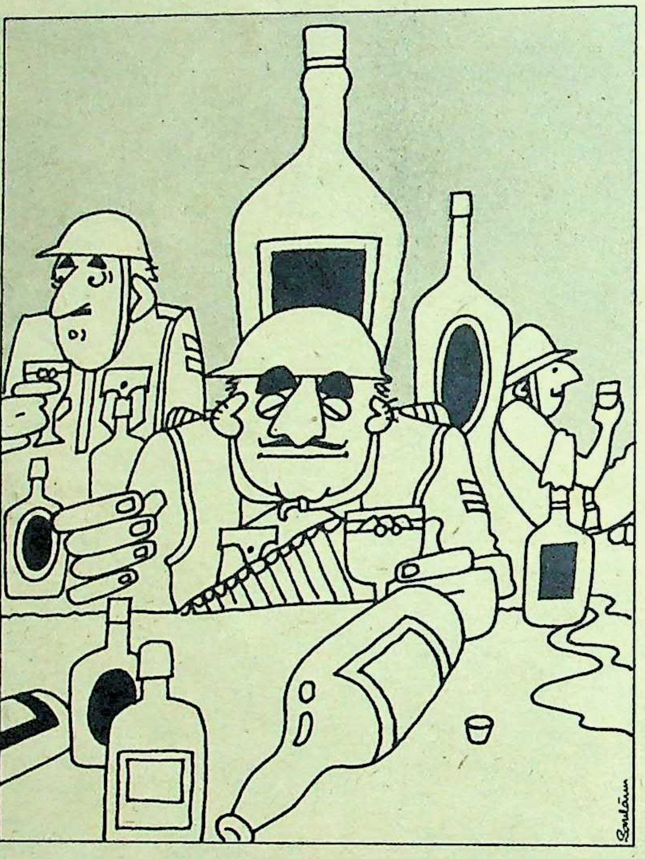

पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बीते साल फौजी कैंटीनों को 'रम' की ५,३०,७७० पेटियां दी गयीं और खप गयीं। यह मात्रा इस अवधि में मिली दूसरी किस्मों की किसी भी शराब से अधिक है। दूसरे नंबर पर 'व्हिस्की' रही, जिसकी ४,००,१६० पेटियां कैंटीनो में आयीं। सशस्त्र सेनाओं के उपभोग के लिए इस क्रम में 'ब्रांडी' की ३,१८,५८५ पेटियां, 'जिन' की ४२,३५० पेटियां, 'वाइन' की ३,४६५ पेटियां, 'लिक्योर' की १,१८६ पेटियां और 'वोदका' की १०० पेटियां कैंटीनो को उपलब्ध करायी गयीं। विचित्र बात यह है कि सैनिक कैंटीनों में अलकोहली पेय के तौर पर सबसे अधिक (१०,२०,२०० पेटी) 'बीयर' लायी गयी। यह सब इंतजाम तकरीबन दस लाख की संख्या-शक्तिवाले रक्षा बल के लिए किया गया।

अलग-अलग कंपनियों से इन कैंटीनों को सप्लाई की गयी पेटियों को यदि आधार माना जाये, तो फौजियों की सबसे पसंदीदा ब्रांड रही, रामपुर डिस्टीलरी ऐंड कैमिकल वर्क्स की 'मेच्योर्ड रम कांटेसा'। इसकी कुल १,१७,००० पेटियां कैंटीनों ने खपायीं, जबकि ब्रिहन महाराष्ट्र शुगर सिंडीकेट से 'नेल्सन रम' की १,०७,९१० और मोहन मिकिंस ब्रिउरी गाजियाबाद से 'ओल्ड मोंक रम' की १,०३,११० पेटियों की खपत हुई। इसी तरह व्हिस्की में मोहन मिकिंस की 'सोलन नं० १' और 'ब्लैक नाइट' पसंद की गयी। इनमें पहली की ४८,१५० और दूसरी की ४७,९२५ पेटियां खपीं।

हमारे फौजी भाइयों को जो दूसरी किस्में पसंद आयीं वे हैं, मोहन मिकिंस की 'गोल्डेन ईगल बीयर' (खपीं ३,६८,३०० पेटियां), अमृत डिस्टीलरीज बंगलौर की 'बिजायस ब्रांडी' (८७,२०० पेटियां), कैर्य ऐंड कंपनी की 'ब्ल्यू रिबन जिन' (१९,४०० पेटियां), शॉ वैलेस की 'रूबी वाइन' (२३१५ पेटियां), सिक्किम डिस्टीलरी की 'कॉफी लिक्योर' (४६८ पेटियां) और निरायु की 'ह्वाइट फील्ड वोदका' (१०० पेटियां)। इनमें वोदका ही एक ऐसी शराब रही जो पूरी-की-पूरी एक ही कंपनी से ली गयी।

ये ब्यौरे देने के साथ ही रक्षा राज्यमंत्री पाणिग्रही ने राज्यसभा को बताया कि अलकोहली पेयों (शराबों) की खरीद के लिए उनके उत्पादकों की सूची तैयार करते समय जो आम कसौटियां रखी गयीं, वे थीं: (क) एक ब्रांड की शराब के लिए एक डिस्टीलरी सूची में रखी जाये, (ख) राष्ट्रव्यापी साखवाली डिस्टीलरियों को महत्व दिया जाये, (ग) सहकारी समितियों, सरकारी प्रतिष्ठानों को भी महत्व दिया जाये। इनमें प्रमुखता विभिन्न क्षेत्रों की उन डिस्टीलरियों, ब्रांडों को दी जाती है, जिन्हें सीएसडी रेंज में प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो और जिनकी तुलना बोतलबंदी संयत्रों से होती हो। तीन साल तक विचाराधीन पड़ी जिन कंपनियों की शराब बाजार में सबसे ज्यादा बिकी हो और जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से परीक्षण में दुरुस्त पाया गया हो, उन्हीं से खरीद को प्रमुखता दी जाती है।

जिन कंपनियों की शराब बाजार में सबसे ज्यादा बिकी हो और जिन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से परीक्षण में दुरुस्त पाया गया हो, उन्हीं से खरीद को प्रमुखता दी जाती है।

—वशिष्ठ

जिन'
लिस की
टियां),
'कॉफी
और
वोदका'
दका ही
री-की-
यी।
ही रक्षा
ज्यसभा
ी पेयों
ए उनके

जन्हें

।

ति समय
वे थीं:
के लिए
ी जाये,
खवाली
ा जाये,
रकारी
जाये।
की उन
ाती है,
निधित्व
तुलना
। तीन
ी जिन
में सबसे
स्वास्थ्य
त पाया
प्रमुखता

-वशिष्ठ

अपने शिशु को प्रोटीन से भरपूर अंडे की पौषकता दीजिए

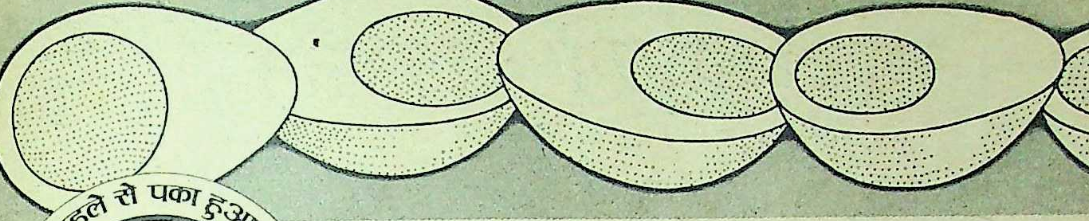

पहले से पका हुआ

फ़ैरेक्स®-एग

६ठे महीने से...

PROTEIN-RICH
Farex®-egg
WITH CEREAL, EGGS AND MILK

नए फ़ैरेक्स-एग में है प्रोटीन. आपके शिशु के चहुमुखी विकास के लिए जिसकी ज़रूरत है.
यह पहले से ही पका हुआ है इसलिए शिशु की कोमल पाचन शक्ति के अनुकूल है.

फ़ैरेक्स. स्वाद भी पाए, बढ़ता भी जाए... मुन्ना.

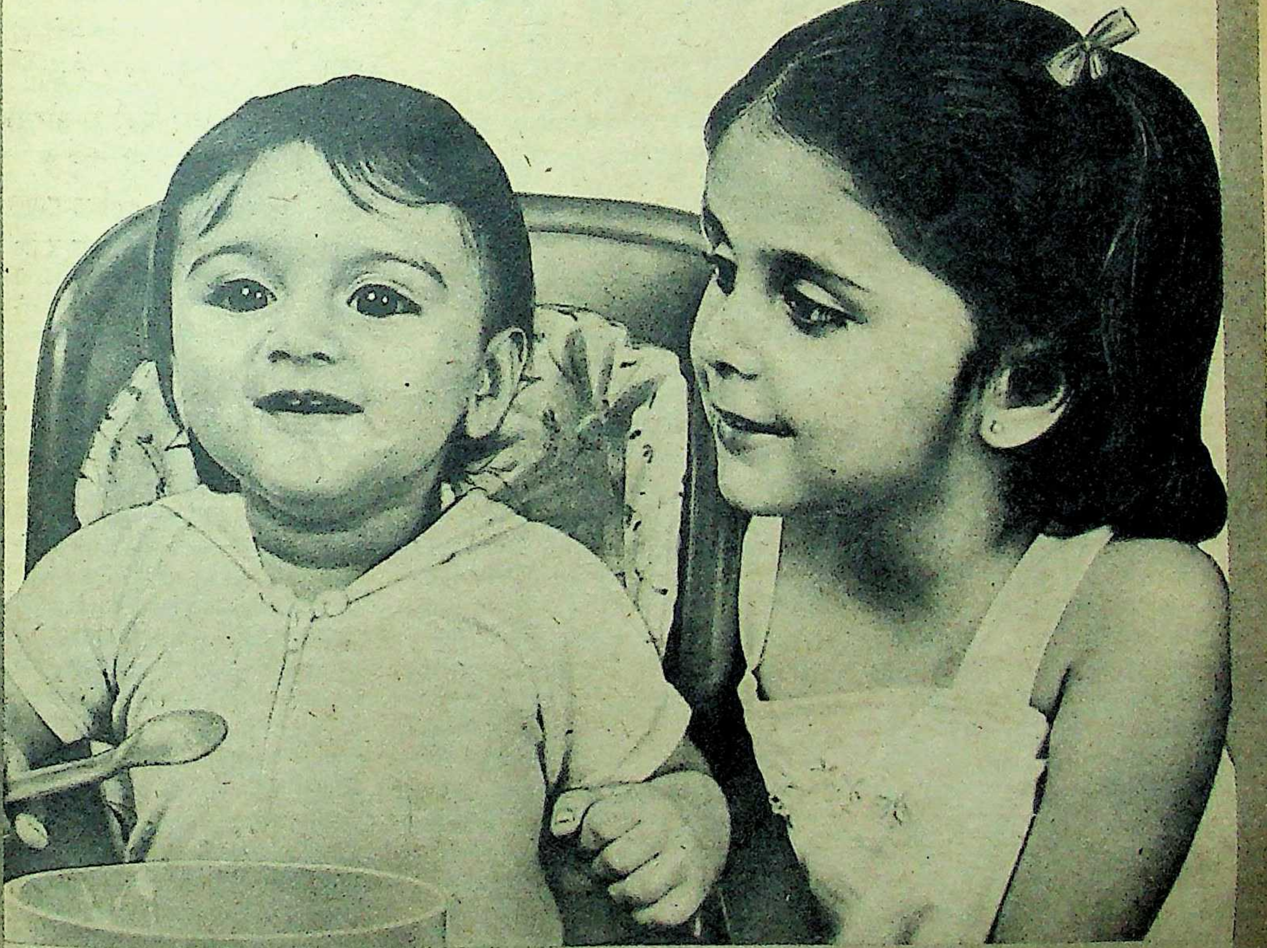

शिशु का सही विकास फ़ैरेक्स-श्रृंखला के साथ १. दूधयुक्त फ़ैरेक्स [illegible] २. फ़ैरेक्स वेज ३. फ़ैरेक्स एग

GX/32/254 HIN

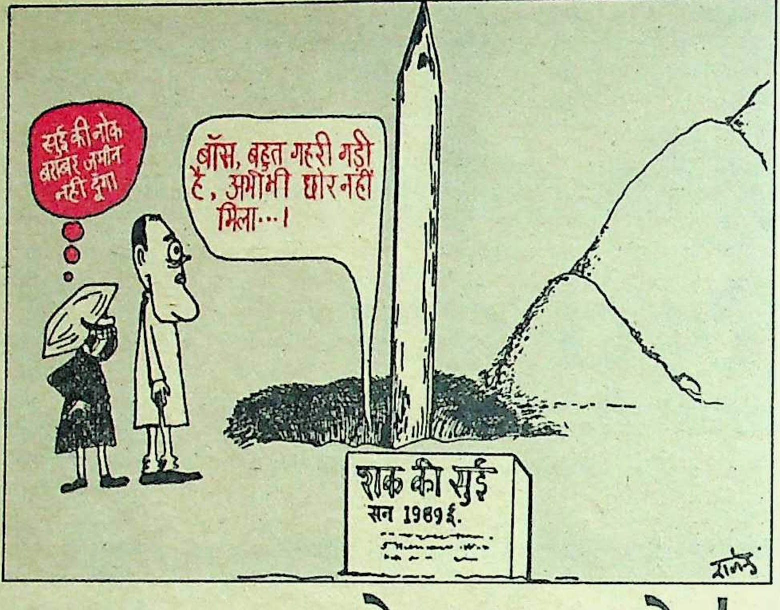
सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा
बॉस, बहुत गहरी गड़ी है, अभीभी छोर नहीं मिला...।
शक की सुई
सन 1989ई.

आजाद कर दो ठक्कर को !

दरबार में गहरा सन्नाटा था। दरबारी भयाक्रांत दीवारों से सटे बैठे थे। बाहर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया था—''ठक्कर (आयोग की रिपोर्ट) को आजाद करो।'' दरबार के गुम्बज में लटक रही 'शक की सुई'...टिक...टिक...करती घूम रही थी। बूटा सिंह सीलड बक्से पर लदे हुए गुरुग्रंथ साहिब का पाठ किये जा रहे थे। विपक्ष के बाहर से आये शोर के जवाब में सीलड बक्से के अंदर से...ठक...ठक...शुरू हो गयी। गहन सन्नाटें में...ठक...ठक...की आवाज ने दिल्ली दरबार की तन्द्रा को तोड़-मरोड़ रखा था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए पूछा—''बूटाजी, यह ठक...ठक...की आवाज कहां से आ रही है? क्या द्वार पर विपक्ष दस्तक दे रहा है?'' बूटा सिंह ने चिदम्बरम् को इशारा करते हुए बक्से पर और जमकर बैठते हुए कहा—''नहीं हुजूर, द्वार पर विपक्ष की कोई दस्तक नहीं है। यह बक्से में बंद अपना मोटा (ठक्कर) अंदर से ठक...ठक कर रहा है।'' इतने में चिदम्बरम् करीब आकर, अपनी लुंगी लपेटकर, बूटा सिंह के बगल में ठक्कर आयोग के सीलड बक्से पर वजन बढ़ाने के लिए बैठ गये। चिदम्बरम् के बैठते ही '...ठक...ठक...' की आवाज फिर से हुई, तो बूटा सिंह ने बड़ी हिकारत भरी नजरों से उनको देखा—''मन भर चावल और सांभर खा लेते हो, लेकिन शरीर का वजन छटांक भर नहीं बढ़ता।'' बूटा सिंह की टिप्पणी पर चिदम्बरम् सकपका गये, तो पास दीवार से सटे पड़े सन्तोष मोहन देव ने अपने मुंह से सिगार निकाल ली और खड़े हो गये। बूटा सिंह ने सन्तोष मोहन देव की तरफ देखते हुए कहा—''देखो, यह पट्ठा है। आ जा सन्तोख, बैठ जा मेरे बगल में। इस लुंगीवाले का इस मोटे पर बैठना, और न बैठना, एक जैसा ही है।'' सन्तोष मोहन देव ने सिगार का धुआं चिदम्बरम् के मुंह पर फेंकते हुए बक्से पर अपना भारी-भरकम शरीर लाद दिया। बक्से के अंदर से...ठक...ठक...की आवाज मंद पड़ गयी। दरबार यह सब कुछ टुकुर-टुकुर निहारते रहे, फिर सहसा वे बोल पड़े—''सभासदो, ठक्कर को आजाद कर देने से क्या मेरे ऊपर काफी प्राबलम आ जायेगी?'' दरबारियों की निगाह बूटा सिंह पर जाकर जम गयी। लेकिन बूटा सिंह के मुंह से कुछ नहीं फूटा। उन्होंने दरबार के प्रश्न को अनसुना-सा करके गुरुग्रंथ साहब का पाठ बुदबुदाना शुरू कर दिया। कल्पनाथ राय से न रहा गया। वे भड़क उठे—''अरे, बूटा क्या बोलेंगे?'' हुजूर, इनसे तो यह पूछा जाये कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट 'लीक' कैसे हुई? हम लोग कितनी मुश्किल से धवन भाई (आरके) को दिल्ली दरबार में लाये, तो इनको सांप सूंघ गया। मुझे सब मालूम है कि कौन क्या गुल खिला रहा है?'' तनाव की स्थिति को रोकने के लिए तुरंत पीवी नरसिम्हाराव उठकर कल्पनाथ राय के करीब आ गये और उनके कंधे पर हाथ रख दिया— ''कल्पनाथजी, आपका दर्द मैं समझ रहा हूं। लेकिन हम लोगों के पास ऐसा कोई आधार अभी तक नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि अमुक व्यक्ति ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट 'लीक' की है।'' कल्पनाथ राय ने नरसिम्हाराव का हाथ अपने कंधे से झटक दिया—''रावजी, आप राय को राय न दें। कल्पनाथ अपनी पैदाइश के साथ ही राय लेकर आया है। वह देखिए 'शक की सुई' घूम-घूम कर बूटा सिंह के सिर पर ही क्यों मंडरा रही है?'' सारे दरबारी 'शक की सुई' की तरफ देखते हुए उठ खड़े हुए। दरबारियों में खुसुरफुसुर शुरू हो गयी—''लगता है कि धवन को ठिकाने लगाने के लिए बूटा सिंह ने ही ठक्कर आयोग की रिपोर्ट 'लीक' की है। बूटा सिंह ने यह अच्छा नहीं किया।'' खुसुरफुसुर में किसी ने कहा—''अच्छा क्या नहीं किया? बूटा सिंह ने ठीक ही किया। जब ठक्कर ने धवन पर शक जाहिर किया, तो उसे उजागर ही होना चाहिए था। इसी खुसरपुसर में एक ऊंचा स्वर जब उभरा, तो दरबारी शांत होकर उधर मुखातिब हो गये। कुरसी पर चढ़े सुमन दुबे ऊंचे स्वर में बोल रहे थे—''अतिरिक्त सूचना सचिव होने के धर्म को निभाने के लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सम्मानित दरबारियो, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब बूटा सिंहजी दरबार के खेतों (कृषि) से निकाल कर गृह मंत्रालय में बिठाये गये, तब तक ठक्कर आयोग की रिपोर्ट 'क्लासीफाइड' हो चुकी थी। इसलिए ठक्कर आयोग की रिपोर्ट की कोई प्रति बूटा सिंहजी के पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप लोग बेकार में बूटा सिंह को संदेह की नजर से देख रहे हैं। वे तो बेचारे किसी तरह गुरुग्रंथ साहिब का पाठ करके अपना गृह मंत्रालय चला रहे हैं।'' सुमन दुबे की घोषणा अभी पूरी भी नहीं हो पायी थी कि दरबार के गुम्बज पर लटक रही

'शक की सुई' बूटा सिंह से घूमकर हेड मास्टर की तरफ आ गयी। दरबारियों ने बहुत ही आश्चर्य भरी नजरों से पहले 'शक की सुई' और उसके बाद घाटे की रोकड़ गिन रहे हेड मास्टर (शंकर राव चह्वाण) की तरफ देखा। हेड मास्टर ने तुरंत घाटे की रोकड गिनना बंद कर दिया—"भाइयो, मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? माना उस समय मैं ही गृहमंत्री था, जब ठक्कर ने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन मेरा उससे क्या लेना देना? जिस दिन रिपोर्ट लीक होकर अखबार में छपी, उसी दिन मैंने सफाई दे दी थी कि दरबार के चचेरे भाई अरुण नेहरू की यह करामात है।" अरुण नेहरू का नाम सुनते ही दरबारियों की चढ़ी त्योरी ढीली पड़ने लगी। शीला दीक्षित ने दरबारियों की भीड़ को पीछे किया और दरबारियों को समझाना शुरू कर दिया—"अब हम लोग उस अप्पू (अरुण नेहरू) का क्या कर सकते हैं? जिस दिन से रिपोर्ट लीक हुई है, हेड मास्टर साहब का ब्लड-प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर उनको कुछ हो गया, तो हमारे घाटे की रोकड कौन गिनेगा? आप लोग शांत रहें।" शीला दीक्षित की बातों ने दरबारियों को और शांत कर दिया। वे लोग अपनी-अपनी जगहों पर जाकर बैठने लगे।

अपनी मूंछों पर खिजाब का ब्रश फेरने के बाद केके तिवारी खड़े हो गये—"अब हम लोग धवनजी पर हो रहे अत्याचारों को और बर्दाश्त नही कर सकते हैं। उनको दरबार में चाणक्य की प्रतिष्ठा अगर नहीं मिली, तो मैं तुरंत एक और बयान दे मारूंगा।" पीछे से कैप्टन सतीश शर्मा ने केके तिवारी की पीठ थपथपायी—"जीते रहो, कागज के शेर।" लेकिन कल्पनाथ राय पंचम में बोल उठे—"अरे तिवारी, तुम तो बयान ही दे मारोगे। अगर धवन भाई के खिलाफ कोई बोला, तो मैं उसे दे मारूंगा।" बूटा सिंह की तरफ देखते हुए कल्पनाथ राय फिर भड़के—"निकालो, इस बक्से से ठक्कर को, मैं अभी उसे ठोंक-पीट कर ठीक किये देता हूं।" कल्पनाथ राय तमतमा कर बूटा सिंह की तरफ बढ़े कि उसके पहले ही एचकेएल भगत भागते हुए दरबार में आ गिरे—"अरे रहने दो कल्पू। मैंने विपक्ष को पूरी तरह ठोंक-पीट कर ठिकाने लगा दिया है। बहुत चहक रहे थे, सबको संसद से ही बाहर करा दिया। अब उनकी अकल ठिकाने आ जायेगी।" कल्पनाथ राय ठिठक कर भगतजी की तरफ निहारने लगे। लेकिन इसी समय पीछे से आकर राव वीरेन्द्र सिंह ने अपनी गर्दन कंधे पर डालकर बोलना शुरू कर दिया—"भगत जी, यह अच्छा नहीं किया। विपक्ष संसद में नहीं रहेगा, तो संसद काहे की?" साथ में आये सीपीएन सिंह ने राव साहब के वाक्य को आगे बढ़ा दिया—"ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में क्या है? यह हमें बताया जाये। अपोजीशन को संसद से बाहर निकालकर यह सवाल मर नहीं गया। हम उठायेंगे कि ठक्कर को आजाद करो। आखिर हम भी चुनकर आये...।" बूटा सिंह ने लपक कर सीपीएन सिंह की गर्दन पकड ली—"अरे पडरौना नरेश, तुम्हारी खिसियान मैं अच्छी तरह समझता हूं। फिर से मंत्री नहीं बन पा रहे हो, तो अब दरबार से गद्दारी करने पर उतर आये हो। ठक्कर आजाद नहीं होगा, तुमको जो करना है, कर लो। मुझे सब मालूम है कि तुम भी राजा मांडा से अंदर-ही-अंदर मिले हो...।" सीपीएन सिंह पलट कर बूटा की गर्दन पकड़ें कि उसके पहले दरबारियों की निगाह 'शक की सुई' पर जाकर टिक गयी। सुई माखनलाल फोतेदार पर खड़ी थी। एक दरबारी ने ऊंचे स्वर में कहा—"छी...छी...! इस कश्मीरी ब्राह्मण (फोतेदार) से यह उम्मीद नहीं थी। अरे दरबार में महत्व, धवन के आने से घटा था, तो इसको यह नहीं करना चाहिए था। इसने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट 'लीक' करके धवन को तो किनारे लगा दिया। लेकिन इससे दरबार को कितनी परेशानी में डाल दिया?" फोतेदार पहले 'शक की सुई' से लुके-छिपे, लेकिन जब उसने उनके ऊपर से हटने से इनकार कर दिया, तो वे तन कर खड़े हो गये—"इस 'शक की सुई' को मेरी तरफ जानबूझ कर मेरी निष्ठा को खतम करने के लिए एक गहरी साजिश के तहत किया गया है। यह सही है कि धवन के आने से मरी हैसियत कम हुई है। लेकिन धवन का कद कम करने के लिए मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता हूं, जिससे दरबार परेशानी में फंस जायें।" दरबारी इस ऊहापोह से निकलें कि ठक्कर को गुपचुप रिहा करने की साजिश इसी फोतेदार ने की है कि उसके पहले रुकी हुई 'शक की सुई' धीरे से खिसक ली। फोतेदार ने रूमाल निकाल कर अपना पसीना पोंछना शुरू कर दिया। सुई खिसकती हुई देखकर कैप्टन सतीश शर्मा ने दरबार के कान में फुसफुसाया—"यार, अब यह तो पता नहीं कि फोतेदार का इस लीकेज में कितना हाथ है। लेकिन पिछले दिनों यह बंबई में एक्सप्रेस से गुपचुप मिला था।" दरबार ने सतीश शर्मा की इस टिप्पणी का कोई उत्तर नहीं दिया, तो वे खिसियाकर दरबार से दूर हट लिये।

> **'शक की सुई'**
> **अभी भी बक्से पर लटक रही थी। दरबारियों में शोर मच गया— "चोर पकड़ गया, चोर पकड़ गया! खुद ठक्कर ने ही अपनी रिपोर्ट लीक की है।" नरसिम्हाराव ने आहिस्ता से कहा, "ठक्कर को उम्मीद थी कि रिपोर्ट देने के बाद उसे किसी अच्छे देश में राजदूत बनाकर भेज दिया जायेगा। शायद इसी कारण खिसियाकर उसने अपनी रिपोर्ट लीक कर दी होगी।**

दरबार में परेशानी बढ़ती जा रही थी। गुम्बज में लटक रही 'शक की सुई' घूमे जा रही थी। दरबारियों की निगाहें उसी पर टिकी थीं। अचानक दरबारियों की बोलती फिर बंद हो गयी। 'शक की सुई' ठक्कर आयोग के सील्ड बक्से पर आकर रुक गयी। बूटा सिंह तो बक्से से पहले ही उठ चुके थे। अपने ऊपर सुई देखकर सन्तोषमोहन देव और चिदम्बरम् भी बक्से के ऊपर से उठ खड़े हुए। 'शक की सुई' अभी भी बक्से पर लटक रही थी। दरबारियों में शोर मच गया—"चोर पकड़ गया, चोर पकड़ गया! खुद ठक्कर ने ही अपनी रिपोर्ट लीक की है।" नरसिम्हाराव ने आहिस्ता से कहा—"ठक्कर को उम्मीद थी कि रिपोर्ट देने के बाद उसे किसी अच्छे देश में राजदूत बनाकर भेज दिया जायेगा। शायद इसी कारण खिसियाकर उसने अपनी रिपोर्ट लीक कर दी होगी। चलो दरबार की समस्या तो यह जानकर दूर हो गयी कि रिपोर्ट ठक्कर ने ही लीक की है।" नरसिम्हाराव की इस टिप्पणी के बाद दरबारियों के चेहरे पर राहत आने लगी। लेकिन बक्से के अंदर से 'ठक...ठक...' होते ही 'शक की सुई' ते खिसकना शुरू कर दिया। दरबारी फिर से परेशानी में फंस गये—"अरे, यह क्या शक की सुई, तो ठक्कर के ऊपर से भी हटने लगी है।"

दरबारी 'शक की सुई' पर नजर गड़ाये-गड़ाये थक कर चूर हो चुके थे। दिल्ली दरबार की परेशानी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। एक़ाएक 'शक की सुई' दिल्ली दरबार के सिर पर आकर रुक गयी। सुई का रुकना था कि दरबार में कोहराम मच गया। "यह क्या? दरबार भी शक के घेरे में आ गये? यह असंभव है।" दिल्ली दरबार ने अपने ऊपर लटक रही 'शक की सुई' से घबरा पंचम स्वर में उद्घोषणा कर दी "अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं किसी को बचाने के लिए खुद शक के घेरे में क्यों फसूं? खोल दो ठक्कर को। आजाद कर दो ठक्कर को। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाये।" दरबार ने जैसे ही ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित करने की उद्घोषणा की, 'शक की सुई' दरबार के सिर से हट कर गुम्बज में जाकर चिपक गयी।

—दरबारी लाल

◆ देश

१६ मार्च : ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सदन में रखे जाने की मांग स्वीकार न होने पर विपक्ष द्वारा राज्य सभा से बहिर्गमन।

१७ मार्च : लोकदल-ब अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा का क्वीवलैंड में निधन। राजस्थान के सभी २७ काबीना मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को त्यागपत्र सौंपे।

१८ मार्च : अकाली दल (लोंगोवाल) दो हिस्सों में बंटा, बलबंत सिह का दल से निष्कासन। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की महासचिव जयललिता द्वारा सक्रिय राजनीति से संन्यास का निर्णय।

१९ मार्च : जार्ज फर्नांडीस जनता दल की राष्ट्रीय अभियान समिति के अध्यक्ष नियुक्त।

२० मार्च : गुरुचरण सिह तोहड़ा का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। बरनाला अकाली दल (लोंगोवाल) के पुनः अध्यक्ष निर्वाचित, किंतु पद लेने से इनकार। स्व० हेमवती नंदन बहुगुणा की इलाहाबाद में अंत्येष्टि।

२१ मार्च : भाकपा का एकता प्रस्ताव माकपा ने ठुकराया। अल्फ्रेड सिल्वेस्टर गोनसालवेस सोवियत संघ में भारत के नये राजदूत नियुक्त। गीत सेठी को हराकर सुभाष अग्रवाल राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियन बने।

२२ मार्च : काबीना सचिव बीजी देशमुख प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नियुक्त।

२३ मार्च : गुजरात के २३ में से २० कांग्रेस-इ सांसदों की राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मांग।

२४ मार्च : जयपुर में उपद्रव, १०० से अधिक मकान, दुकान एवं गोदाम क्षतिग्रस्त ।

२५ मार्च : प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित। तमिलनाडु विधानसभा में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष में मारपीट, एक मंत्री घायल, जयललिता सहित २८ अन्नाद्रमुक विधायक निलंबित।

२६ मार्च : अन्नाद्रमुक के विलय विरोधी नेता आरएम वीरप्पन द्वारा नये दल अन्नाद्रमुक (एमजीआर) का शुभारंभ। नाथूराम मिर्धा राजस्थान राज्य जनता दल के अध्यक्ष नियुक्त।

२७ मार्च : श्रीमती गांधी हत्याकांड से संबंधित ठक्कर रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश। पूर्व विधि मंत्री हिदायतुल्ला खान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित। मुख्यमंत्री देवीलाल द्वारा हरियाणा के काबीना कृषि मंत्री तैयब हुसैन मंत्रिमंडल से निष्कासित।

२८ मार्च : ठक्कर रिपोर्ट को लेकर लोकसभा की कार्रवाई दो बार निलंबित, बिहार विधानसभा में भी हंगामा।

२९ मार्च : केहर सिंह के पुत्र राजिंदर सिंह द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में १० लाख रुपए के दावे की याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल।

३० मार्च : केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्निरीक्षण के लिए नियुक्त सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लेकर संसद में विवाद। हरियाणा में मुख्यमंत्री देवीलाल के छोटे पुत्र रंजीत सिंह सहित पांच नये चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल।

३१ मार्च : मान्यता के लिए जनता दल द्वारा संसद के दोनों सदनों में दस्तावेज पेश। सरला ग्रेवाल द्वारा मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण।

एमपी ठक्कर

जयललिता

नजीबुल्ला

नुसरत भुट्टो

◆ विदेश

१६ मार्च : इस्लामी संघ सम्मेलन के विदेश मंत्रियों द्वारा 'सेटेनिक वर्सेज' के लेखक सलमान रुश्दी की हत्या के लिए ईरानी धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी का आह्वान नामंजूर। भारतीय मूल की युवती पामेला बोर्डेस द्वारा ब्रिटिश सरकार गिराने की कीमत के रूप में १० लाख पाउंड (लगभग दो करोड़ ६५ लाख रुपए) की मांग।

१७ मार्च : जलालाबाद शहर पर मुजाहिदीनों का आक्रमण, ३०० विद्रोही मारे गये।

१८ मार्च : चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति गुस्ताव हुसक की हत्या का प्रयास विफल।

१९ मार्च : केन्याई धावक जान नुगी का लगातार चौथी बार विश्व क्रासकंट्री उपाधि जीतने का रिकार्ड।

२० मार्च : यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) का ईरान से अपना राजदूत वापस बुलाने का निर्णय रद्द।

२१ मार्च : ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा एम १५ का पामेला बोर्डेस को 'क्लीन-चिट'। कराची में दंगा, २०० वाहन फूंके गये। एल सल्वाडोर को अमरीकी आर्थिक तथा सैनिक सहायता जारी रखने का अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश का निर्णय।

२२ मार्च : सिंहलियों द्वारा श्रीलंका में हड़ताल।

२३ मार्च : पाकिस्तानी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मां नुसरत भुट्टो को काबीना में लिये जाने का ऐलान। अमरीका से सोवियत संघ का व्यापार प्रतिनिधि निष्कासित।

२४ मार्च : पाकिस्तान स्थित शरणार्थी कैंप से अफगानिस्तान सीमा पार करने के प्रयास में खैबर दर्रे के समीप १९ अफगान महिलाएं पाक सैनिकों की गोली से मृत। बांग्ला देश के प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति इरशाद के सत्ताग्रहण के वार्षिक दिवस के विरोध में 'काला दिवस' मनाया गया।

२५ मार्च : अफगान मुजाहिदीनों का जलालाबाद शहर पर अधिकार करने हेतु पहली बार टैंकों एवं फौजी गाड़ियों के साथ प्रयास।

२६ मार्च : सोवियत रूस में अपने प्रकार की पहली 'सुपर संसद' के लिए बहु-प्रतियोगी चुनाव का पहला दौर संपन्न। लेबनान में विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष।

२७ मार्च : बोरिस येल्तसिन सुपर संसद के लिए मास्को नगर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित।

२८ मार्च : संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जाफर का पद से त्यागपत्र। आस्ट्रेलिया के दूर-संचार तथा उड्डयन मंत्री गैरीपंच का पद से त्यागपत्र।

२९ मार्च : सलमान रुश्दी के मामले पर मिली मौत की धमकी के बाद बेल्जियम की सबसे बड़ी मस्जिद के ईमाम तथा उनके सहायक की गोली मारकर हत्या। हंगेरियाई जहाज के दोनों अपहर्ताओं द्वारा प्रेग (चेकोस्लोवाकिया) में आत्मसमर्पण।

३० मार्च : अफगानिस्तान समस्या के हल के लिए राष्ट्रपति नजीबुल्ला तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र से की गयी हस्तक्षेप की अपील अमरीका द्वारा रद्द। फास्टर तथा डस्टिन हाफमैन (दूसरी बार) को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आस्कर पुरस्कार।

३१ मार्च : पाकिस्तान में नुसरत भुट्टो द्वारा काबीना मंत्रिपद की शपथ ग्रहण। चर्चित भारतीय सुंदरी पामेला बोर्डेस 'बाली' द्वीप में सड़क दुर्घटना में घायल।

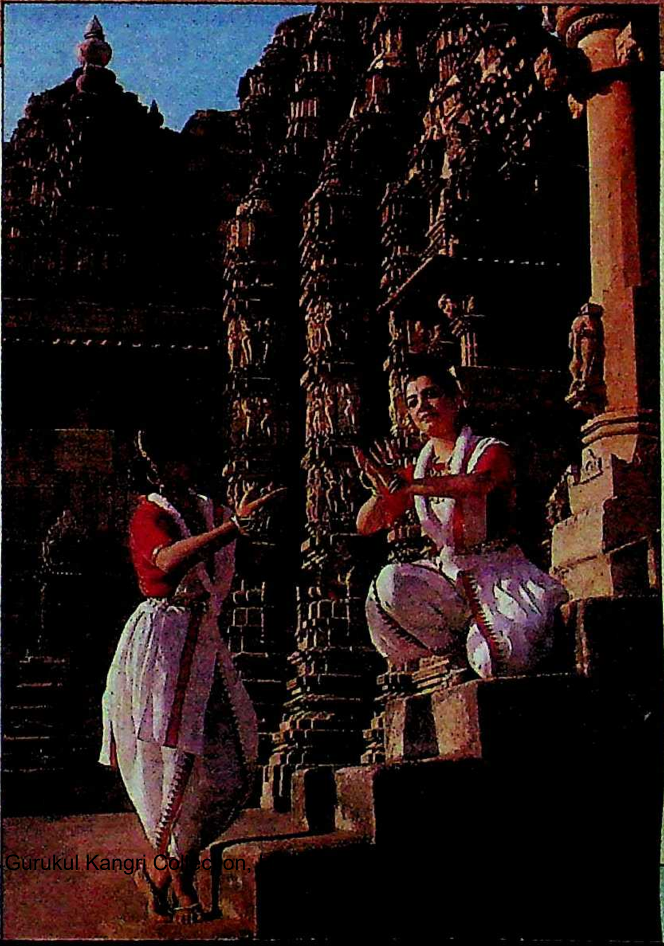

९वीं और १२वीं शताब्दी के बीच चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर विश्व में मूर्ति-निर्माण और मंदिर-शिल्प के अनुपम उदाहरण हैं। प्रेम, सौंदर्य,शृंगार और दर्शन को बलुए पत्थरों में बेनाम शिल्पियों ने जिस जीवंतता से ढाला है, वह अभूतपूर्व है। यद्यपि समय, परवर्ती शासकों तथा विकृत और अपराधी मानसिकता ने इन मंदिरों और उनमें जड़ी प्रतिमाओं को अखंडित नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी ये पर्यटकों, अध्येताओं,शोधकर्ताओं के लिए अदम्य आकर्षण के केंद्र हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग की ओर से यहां हर वर्ष 'खजुराहो महोत्सव' का आयोजन भी होता है। इस वर्ष २६ फरवरी से ४ मार्च तक यह महोत्सव आयोजित हुआ और लब्धप्रतिष्ठ कलाकारों ने खजुराहो की पृष्ठभूमि में उसी तरह की कुछ भाव मुद्राओं को अभिव्यक्ति देने की कोशिश की, जैसी भावमुद्राएं खजुराहो की प्रतिमाओं से प्रकट होती हैं (ऊपर और नीचे दायें)।

छाया : उपेंद्र वाजपेयी

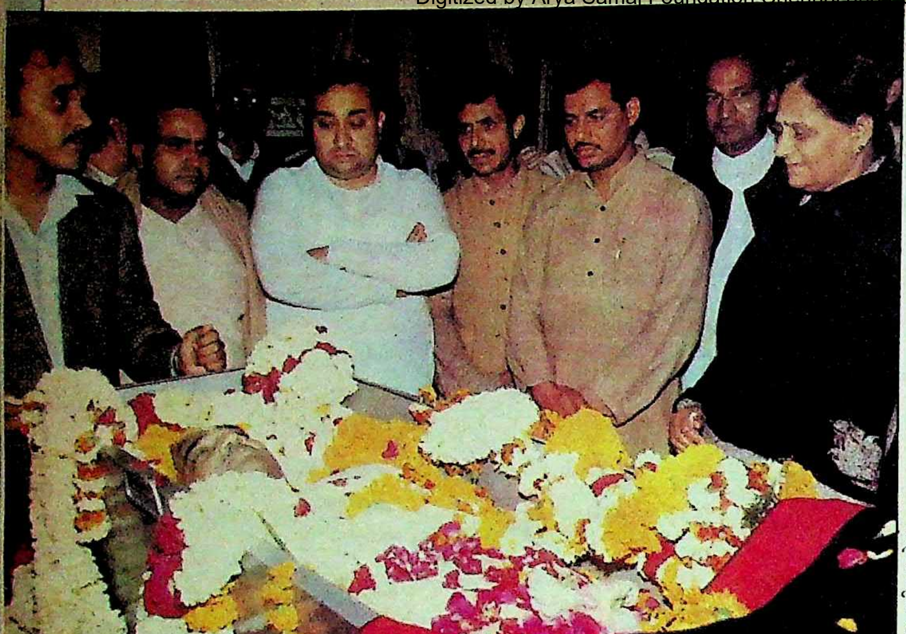

छाया : सुनील सक्सेना

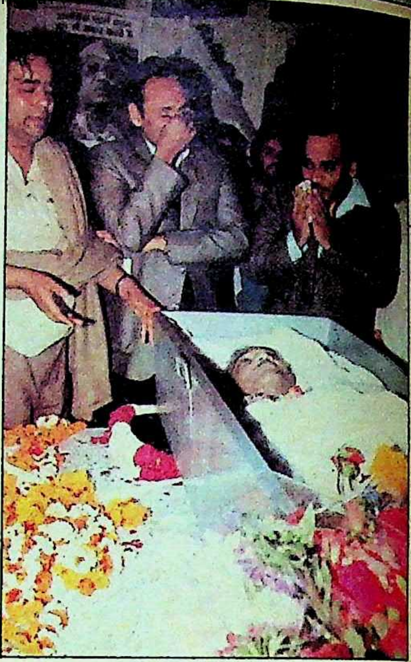

छाया : वसीमुल हक

भारतीय राजनीति में स्थायी और अलग पहचान बनाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को कोई चुप नहीं कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से २० मार्च को वे चिरंतन चुप्पी के साथ स्वदेश लौटे। उनकी यह चुप्पी उनके स्वजनों (ऊपर एकदम बायें पुत्र शेखर और एकदम दायें पत्नी कमला बहुगुणा) और परिजनों से देखी नहीं गयी और वे बिलख पड़े। स्वर्गीय बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्री-पदों की शोभा बढ़ा चुके थे, इसलिए राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इलाहाबाद में उनकी अंतिम यात्रा में विशाल जनसमूह (नीचे बायें) उमड़ पड़ा। इलाहाबाद में छात्र राजनीति के वे जनक थे। उनके द्वारा तैयार किये गये शोकसंतप्त युवा नेता उनकी शवयात्रा में अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे, जिनमें प्रमुख थे विधायक अनुग्रह नारायण सिंह और सुभाष चंद्र त्रिपाठी।

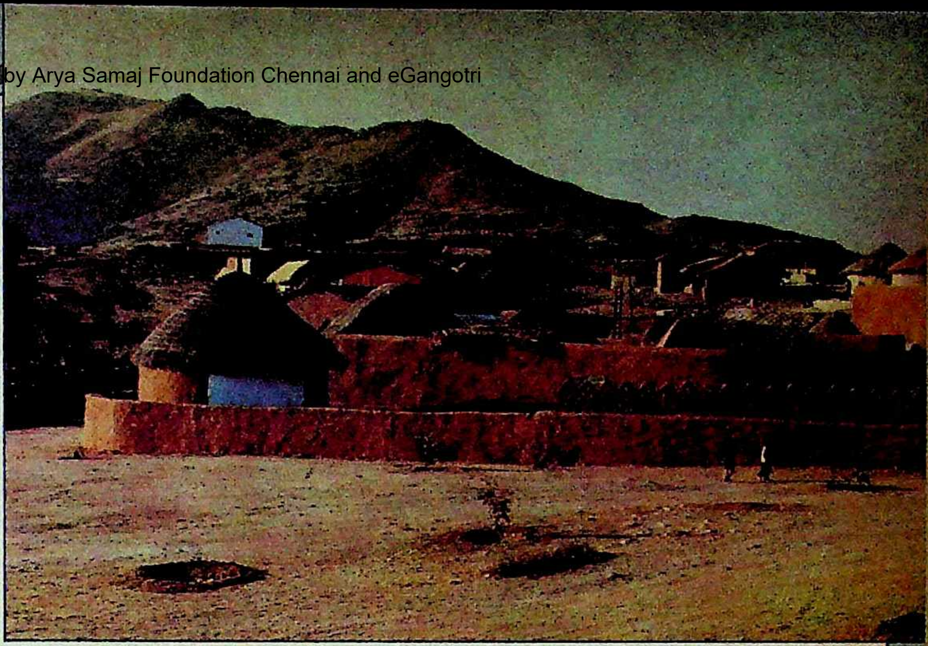

ग्रामीण संस्कृति और स्मृति के संरक्षणार्थ पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ने हाल ही उदयपुर से ६ किमी दूर हवाला गांव में १३० बीघे के बंजर भूखंड में २६ लाख रुपए के व्यय से एक गांव बसाया। चार राज्यों—राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा—की ठेठ लोकसंस्कृति तथा ग्रामीण झोंपड़ियोंवाले इस गांव में विभिन्न अंचलों के ग्रामीण कलाकारों और शिल्पियों को सपरिवार बसाया गया है, नतीजतन लोक-स्वरलहरियों, थिरकनों से जीवंत गांव कला, संस्कृति, शिल्प, स्थापत्य का लोकसंगम बन गया है और इसीलिए इसका नाम भी 'शिल्पग्राम' रखा गया है। यह गांव एक अनूठा पर्यटन-स्थल बनता जा रहा है। शिल्पग्राम की सबसे बड़ी खूबी इन राज्यों के विभिन्न अंचलों से लाकर यहां जस-की-तस स्थापित की गयी झोंपड़ियां हैं। ऐसी ही मौलिक चीज है जैसलमेर की रामा झोंपड़ी जिसके पीछे है शिल्पग्राम का विहंगम दृश्य (ऊपर दायें)। गत ८ फरवरी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिल्पग्राम का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, शिल्पग्राम के डिजाइनर हकू भाई शाह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत; कार्यवाहक राज्यपाल जगदीश शरण वर्मा तथा संस्कृति मंत्री बीना काक के साथ ग्राम का नजारा लिया (बीच में बायें)। यहां टेरीकोटा का काम करते हुए गुजरात के कुम्हार मसलन मोती चोलिया (नीचे बायें) और आगंतुकों का स्वागत निश्छल मुस्कान के साथ करती कुमारी जस्सू भोपी (बीच में दायें) ने दर्शकों का ध्यान बरबस खींच लिया।

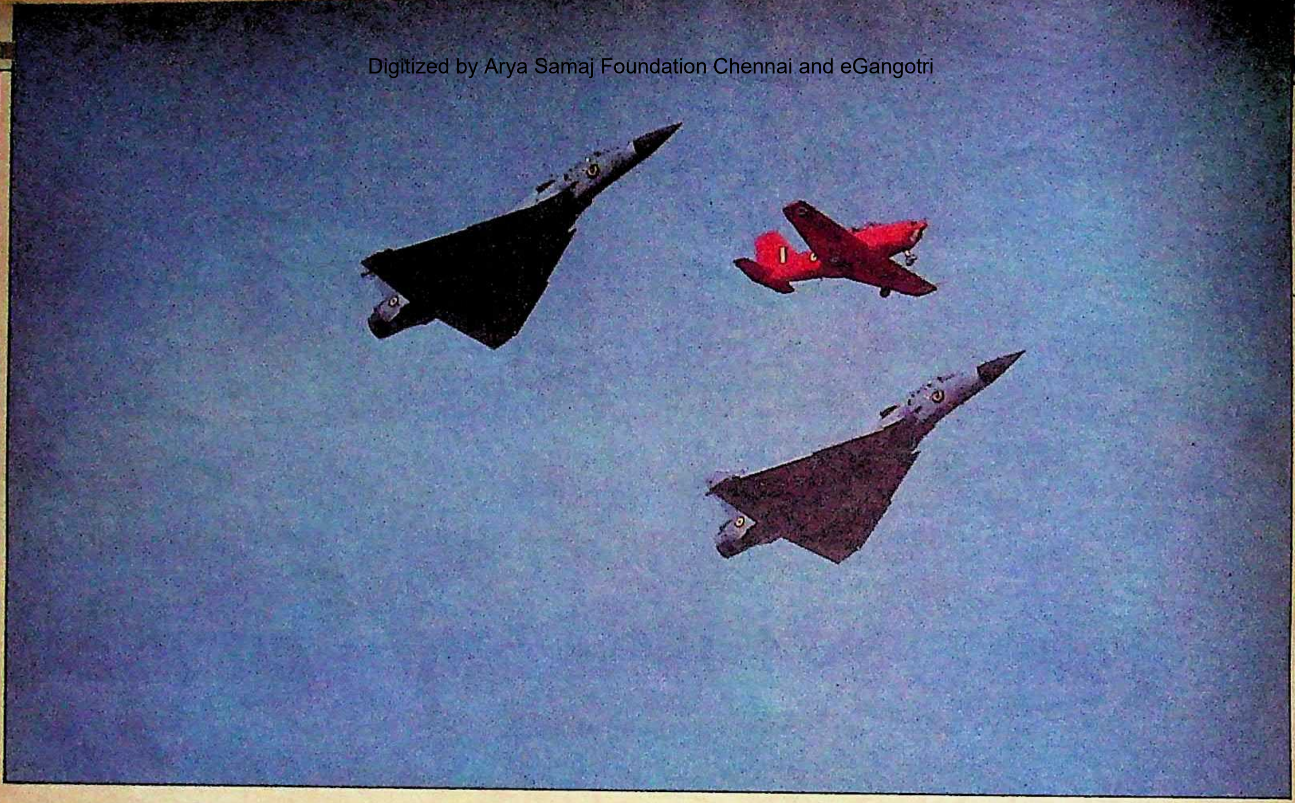

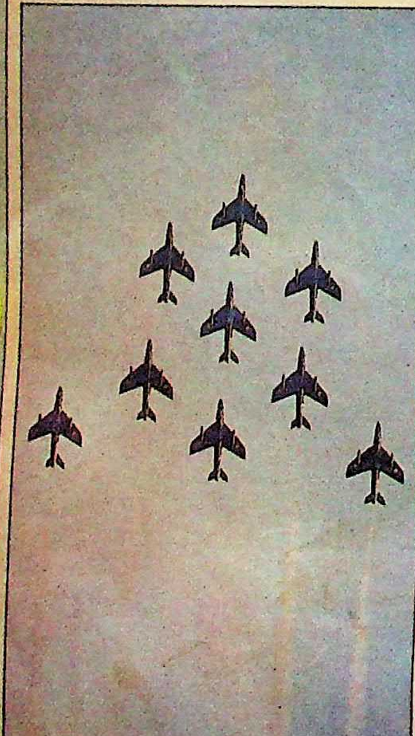

सात साल के अंतराल के बाद १८ मार्च '८९ को फरीदाबाद के निकट तिलपत नामक स्थान पर भारतीय वायुसेना ने अपने एक घंटे इकतालीस मिनट के कार्यक्रम में अपनी अचूक निशानेबाजी, जबर्दस्त प्रहार करने की कला तथा रोमांचक हवाई कलाबाजियां दिखाकर देशवासियों के इस विश्वास को और मजबूत कर दिया कि देश की वायुसेना भारतीय नभ सीमा की सजग प्रहरी है। इस अवसर पर वायुसेना के १२७ विमानों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया, जिनमें जगुआर, मिग-२१, मिग-२३, मिग-२७, मिग-२९, मिराज-२०००, आईएल-७६, एएन-३२ शामिल थे। इसके अतिरिक्त विश्व के सबसे बड़े हेलीकाप्टर एमआई-२६ का भी प्रदर्शन किया गया, साथ में एमआई-२७ तथा एमआई-१७ भी मौजूद थे। वायुसेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति आर वेंकटरमण, उपराष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और रक्षामंत्री कृष्णचंद्र पंत मौजूद थे। तीन चरणों में पूरे हुए इस कार्यक्रम में जहां वायुसेना ने युद्ध-क्षेत्र में निभायी जाने वाली अपनी महत्वपूर्ण, साहसिक और नाजुक भूमिका का प्रदर्शन किया, वहीं लोमहर्षक हवाई कलाबाजियां दिखाकर भारतीय वायुसेना ने अत्याधुनिक तकनीक का परिचय दिया। पृथ्वी से लगभग १०० फुट की ऊंचाई पर तीव्र गति से उड़ते हुए रंग-बिरंगे विमानों (देखें चित्र) द्वारा क्षेत्र-रक्षण तथा दुश्मनों को चकमा देकर अपने साथी विमान को बचाकर लाने की कला सराहनीय रही। यही नहीं, चार किलोमीटर की परिधि में फैले १२ ठिकानों पर अचूक बमबारी का प्रदर्शन भी किया गया।

छाया : सुनील सक्सेना

Raymond
CEMENT

जब किसी निर्णय पर सालों-साल साथ निभाने की बात निर्भर हो तो ठोस प्रमाण उसमें मदद करते हैं

प्रमाण १ : गुणवत्ता
रेमण्ड का नाम ही सर्वोच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय है.

प्रमाण २ : मज़बूती
बी आइ एस के मानकों से निश्चय ही ज़्यादा 'कॉम्प्रेसिव' शक्ति.

प्रमाण ३ : ब्लेन
महीनतम ब्लेन के कारण अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मनचाही मज़बूती की गारंटी.

प्रमाण ४ : जमाव गुण
रेमण्ड सीमेंट पूर्ण जमाव का आश्वासन देता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव की अवधि बी आइ एस मानकों से बेहतर है.

प्रमाण ५ : विक्रेताओं का जाल
देशभर में रेमण्ड के अधिकृत विक्रेताओं का जाल शत प्रतिशत असली सीमेंट उपलब्ध कराता है.

प्रमाण ६ : पैकेजिंग
स्वचालित रोटरी पैकेजिंग मशीनों द्वारा सबसे मज़बूत प्लास्टिक और जूट की बोरियों में पैक याने निकाल लिए जाने का अंदेशा ही नहीं.

प्रमाण ७ : बचत
कोई अन्य सीमेंट हर बार इतने ठोस लाभों की गारंटी दे नहीं सकते.

प्रमाण ८ : हमारे कुछ ग्राहक
एन टी पी सी, ऑयल इंडिया लि., भारतीय रेलवे्ज़, वायजैक़ स्टील प्लांट, ईस्ट इंडिया होटल्स लि., आइ टी सी लिमिटेड, वोल्टास लि., टाटा रोबिन्स फ्रेसर, निटको टाइल्स, अंसल हाउसिंग प्रा. लि., एस.आर.एफ. निप्पॉन डेनरो इस्पात लि. जी.ई.सी.

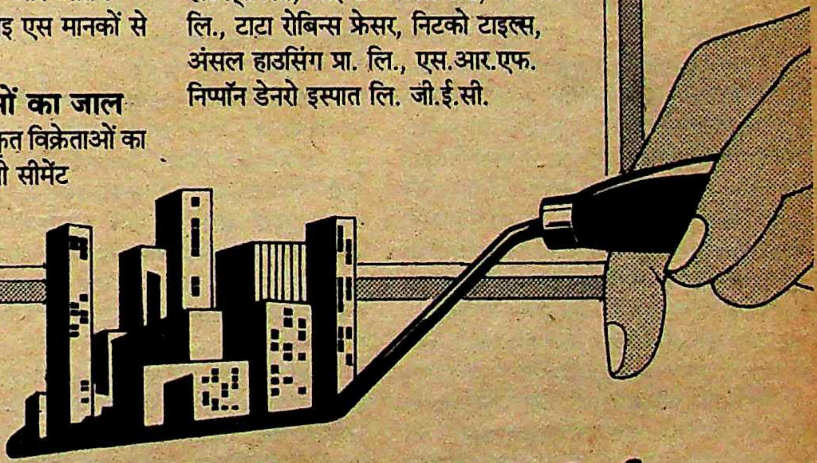

कैलाश सीमेंट : निर्माता

रेमण्ड

गुणवत्ता का दूसरा नाम.

जनता दल

चंद्र शेखर बनाम वीपी सिंह

२० फरवरी को महाराष्ट्र प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चंद्र शेखर और वीपी सिंह के बीच जिस तानाकशी से शीतयुद्ध शुरू हुआ था, वह फिलहाल थम तो गया है, किंतु राजनीतिक पर्यवेक्षक इस खामोशी को तूफान से पहलेवाली खामोशी का नाम दे रहे हैं। जनता दल को तोड़ने की चंद्र शेखर की धमकी क्या महज तात्कालिक गुस्से की उपज थी या वीपी सिंह के नेतृत्व के प्रति उपेक्षा की स्थायी भावना की अभिव्यक्ति? चंद्र शेखर और वीपी सिंह के बीच यदि प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, तो अंजाम क्या होगा?

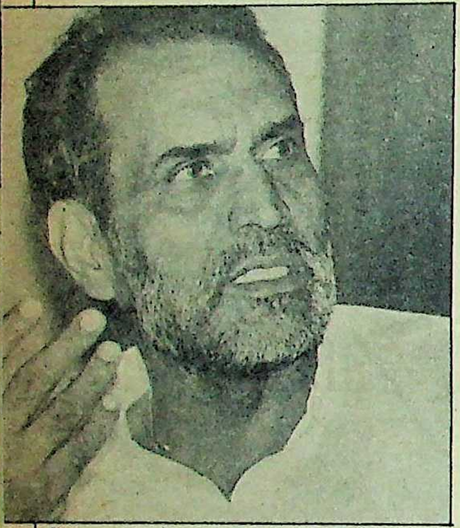

मैं जनता दल तोड़ सकता हूं: चंद्र शेखर

राजनीतिक हलकों में कुछ समय से यह बात गर्म थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इंडोनेशियाई द्वीप समूह के कुछ बैंकों में जो पैसे गोपनीय ढंग से जमाकर रखे हैं, उन खातों के नंबर जनता के सामने पेश कर दिये जायेंगे, जिससे उनकी साफ-सुथरी छवि दागदार हो जायेगी। बाद में उनकी बाकी रह गयी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने के लिए उनके तथाकथित स्विस बैंक एकाउंट का पर्दाफाश किया जायेगा। जनता दल के एक और प्रमुख नेता और वीपी सिंह को आगे बढ़ाने वाले देवी लाल के साथ भी यही होगा।

इस तरह की बातें चाहे जिस किसी ने भी उठायी हों, इससे शासक दल के उन सदस्यों का मनोबल बढ़ा जो वाशिंगटन में माइकेल हर्शमैन से मिलने के बाद सुब्रह्मण्यम स्वामी के जरूरी दस्तावेजों के साथ लौटने का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। वीपी सिंह और देवी लाल के बारे में इस तरह की अफवाहें उठने से विपक्ष की राजनीति पर भी काफी असर हुआ। अजीत सिंह द्वारा अपनी निष्ठा बदलने (चंद्र शेखर से दूर होने) और वीपी सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जनता दल में जो शीत युद्ध चल रहा था, उसमें गरमाहट आयी और वहां आपसी सद्भाव का जो नाजुक माहौल बनता महसूस हो रहा था, वह टूट गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी पहली झलक तो २० फरवरी, १९८९ को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बलिया और मांडा के ठाकुरों के बीच खुली टकराहट के रूप में दिखी।

चंद्र शेखर की धमकी: हुआ यह है कि राजनीति में बहुत सावधानी से दांव चलने, विवादों से बचने की कोशिश करने तथा अपने राजनीतिक 'गुरु' जयप्रकाश नारायण की तरह सत्ता से दूर रहने वाले चंद्र शेखर उस दिन वीपी सिंह पर भ्रामक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बरस पड़े। ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। उन्होंने वीपी सिंह पर आरोप लगाया कि वे दल के कामकाज ठीक ढंग से नहीं चला रहे हैं। उन्होंने कहा, "इसी कारण इंदुभाई और अन्य लोग दल से बाहर हैं। मुझे हल्के तौर पर न लें। कोई भी आदमी अपरिहार्य नहीं है। मैं एक संवाददाता सम्मेलन बुला कर एक वाक्य कह कर ही अभी भी दल को तोड़ सकता हूं।" पहली बार ये दो ठाकुर नेता इतने खुलेआम ढंग से लड़े। कहते हैं कि सिंह ने जवाब दिया, "मैं ऐसी भाषा का आदी नहीं हूं।" लेकिन चंद्र शेखर का गुस्सा थमा नहीं। अंदर का उबाल, उस दिन बाहर का मौसम एकदम ठंडा होने पर भी, बाहर निकल ही आया। वैसे हाल का माहौल तो गरम ही था। बीजू पटनायक के चेहरे पर तमतमाहट के कारण पसीने की बूंदें निकल आयी थीं। अरुण नेहरू बेचैनी से अपनी कुरसी पर बैठे थे। ऐसा लगा कि दल के टूटने के लिए अब प्रेस कांफ्रेंस में चंद्र शेखर के एक शब्द कहने की जरूरत भी नहीं रह गयी है।

विवाद शुरू हुआ मृणाल गोरे को महाराष्ट्र प्रदेश जनता दल का अध्यक्ष बनाये जाने के मसले पर। चंद्र शेखर चाहते थे कि मृणाल की जगह पीके अन्ना पाटिल ही महाराष्ट्र के प्रमुख बने रहें। उन्हें बताया गया कि यह फैसला एक दिन पहले ही, यानी १९ फरवरी को किया जा चुका है। उस दिन शाम को बैठक हुई थी और उसमें किसी ने भी इस नाम पर आपत्ति नहीं की थी। चंद्र शेखर का गुस्सा तब फूट पड़ा जब वीपी सिंह ने कहा कि नयी नियुक्तियां करने से पहले यह नीति ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ८० फीसदी स्थान पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, हरिजनों और औरतों को दिये जाने हैं। चंद्र शेखर को लगा कि वीपी सिंह कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहे हैं और वे बिहार जनता दल के अध्यक्ष पद पर उनके आदमी रघुनाथ झा के चुनाव के मुद्दे को फिर से उठाना चाहते हैं। इसी के बाद वे उखड़ गये।

सख्त होने की कोशिश: वीपी सिंह

दोनों ठाकुरों की तेज भिड़ंत के बीच देवी लाल को लगा कि सिंह उनके आदमी लालू प्रसाद यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने के मुद्दे को भी फिर से खोलना चाहते हैं। इसके बाद देवी लाल भी, जो बातों की मीठी छुरी चलाने के लिए विख्यात नहीं हैं, सिंह की आलोचना में चंद्र शेखर के साथ हो लिये।

वीपी सिंह के लिए तो यह हद ही थी। अब तक का उनका सबसे बड़ा समर्थक ही उनकी आलोचना कर रहा था। बैठक से उठते हुए उन्होंने कहा, "अगर आप सभी लोगों को पार्टी का काम चलाने की मेरी क्षमता में विश्वास नहीं है, तो मैं ही चला जाता हूं।" इस पर देवी लाल ने कहा, "जाओ, जाओ" और सिंह तेजी से बाहर निकल गये। देवी लाल के सिपहसालार शरद यादव और अजीत सिंह ने स्थिति को संभाला। वे दौड़कर गये और किसी तरह सिंह को मना लाये। उन्हें घेर कर लानेवालों में से एक ने कहा, "आप क्या कर रहे हैं? सारा खेल समाप्त हो जायेगा। चंद्र शेखर के फंदे में

मत पड़िये।" लोगों के मनाने पर वीपी सिंह वापस आ गये थे। इस बार देवी लाल ने बड़ी उदारतापूर्वक उनका स्वागत किया।

आपसी कलह की परिणति: २० फरवरी को जो कुछ हुआ वह मन की जलन और कलह का नतीजा था। दो दशकों से चंद्र शेखर के सहयोगी और प्रशंसक रहे व्यक्ति का कहना है कि इसका चंद्र शेखर की छवि पर खराब असर होगा। वे कहते हैं, "तलवार का काटा जुड़ सकता है, मगर जुबान का काटा कभी नहीं।" सच तो यह है कि २० फरवरी को दोनों ठाकुरों के बीच पनपी तनातनी भरी 'सौहार्द्रता' भी उस दिन टूट गयी। हालांकि दोनों ने ही इस घटना का कहीं जिक्र नहीं किया और न ही उसके बाद कलह बढ़ानेवाला कोई काम ही किया। लेकिन यह मान लेना असंभव है कि वे जल्दी ही इस विवाद को भूल जायेंगे। इस झगड़े के दूरगामी परिणाम जनता दल और बड़े विपक्षी नेताओं के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे।

फिर भी, इतना तो है ही कि २० फरवरी को वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के बीच जिस किस्म की तानाकशी हुई उसने विपक्षी एकता को पुनः एक बार संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। जाहिर है, जनता का सहयोग विपक्ष को तभी मिल सकता है जब जनता को विपक्ष की मजबूत एकता पर विश्वास हो जाये। किंतु जब आम आदमी विपक्षी एकता के नाम पर हो रहे युद्ध को मद्देनजर रखता है, तो उसे विपक्षी एकता बेदम नजर आती है। २० फरवरी को चंद्र शेखर अचानक इतना क्यों उबल पड़े या उन्होंने दल तोड़ने की धमकी क्यों दे दी, इसका कोई ठोस कारण तो नहीं बताया जा सकता, किंतु इतना जरूर है कि उनके आलोचक इस उबाल को उनकी बदली हुई मानसिकता से जोड़ते हैं। इस संबंध में उनके आलोचकों का कहना है कि १९८५ के बाद से चंद्र शेखर की राजनीति सिर्फ सबसे बड़ा पद पाने की ही रही है। उन्हें तब लगा था कि श्रीमती गांधी की लोकप्रियता समाप्त हो गयी, क्योंकि गुंडूराव, अब्दुल रहमान अंतुले और जगन्नाथ मिश्र वगैरह ने कांग्रेस पार्टी को काफी बदनाम कर दिया था और अमेठी में मेनका गांधी राजीव गांधी के लिए एक खतरा बनी थीं। ऐसी स्थिति में जनता पार्टी का शासन में आना बहुत संभव था। इसलिए और भी क्योंकि जनता पार्टी ने कर्नाटक में चुनाव जीत लिया था और श्रीमती गांधी कर्नाटक में भी हार गयी थीं। चंद्र शेखर के सामने जो राजनीतिक माहौल था उसमें उन्हें ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र में शरद पवार, प० बंगाल में ज्योति बसु और बिहार में कर्पूरी ठाकुर भी खुशी-खुशी उन्हें समर्थन देंगे। कन्याकुमारी से राजघाट तक की ४२६० किमी लंबी पदयात्रा का उद्देश्य खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताना था।

यही आरोप स्वामी अग्निवेश का भी है। उनके अनुसार चंद्र शेखर की यह पूरी योजना श्रीमती गांधी की हत्या और उससे पैदा सहानुभूति लहर के कारण धरी की धरी रह गयी। इस संबंध में कर्नाटक के एक मंत्री बताते हैं कि इसके बाद चंद्र शेखर ने इस बात का खास ध्यान रखा कि विपक्ष के किसी अन्य नेता की राष्ट्रीय हैसियत न बने। इस मंत्री ने कहा, "देवी लाल द्वारा लाख कोशिश करने पर भी उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन नहीं किया।" आलोचकों का कहना है कि चंद्र शेखर ने भांप लिया था कि हिंदीभाषी इलाके में हरियाणा इंका की पकड़ से बाहर जाने वाला पहला राज्य होगा और यहां जीतने के साथ ही देवी लाल राष्ट्रीय नेता बनकर उभरेंगे।

इस मंत्री ने आगे कहा, "राष्ट्रीय नेता के रूप में

साक्षात्कार/सुब्रह्मण्यम स्वामी

मैं नहीं कह सकता कि चंद्र शेखर प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं

"मेरी चंद्र शेखर से पहली मुलाकात १९७४ में तब हुई थी, जब हम दोनों उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गये थे। हम १९७४ से १९७७ तक अच्छे दोस्त थे। हमारे संबंधों में १९७७ से १९८० के बीच तनाव पैदा हुए। इसका कारण अटल बिहारी वाजपेयी से मेरा झगड़ा था। चंद्र शेखर ने वाजपेयी का बचाव करने की कोशिश की थी। किंतु वाजपेयी की जनता पार्टी की अलहदगी के बाद हमारे संबंध फिर सौहार्द्रपूर्ण हो गये। हम फिर १९८२ तक दोस्त बने रहे। उसके बाद राम कृष्ण हेगड़े चंद्र शेखर का कान यह कहकर भरने लगे कि मोरारजी देसाई मुझे जनता पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए पाल-पोस रहे हैं। हमारे (स्वामी-चंद्र शेखर के) बीच दुश्मनी पैदा करने में हेगड़े ने अहम भूमिका निभाई। यद्यपि हेगड़े को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने वाले खुद चंद्र शेखर थे, किंतु हेगड़े ने उनसे भी गद्दारी की। हालात में फिर तब्दीली आयी। व्यावहारिक राजनीतिज्ञों की तरह चंद्र शेखर और मैंने भेंट कर पुराने वैर-भाव भूल जाने का फैसला किया। वैसे चंद्र शेखर के खिलाफ मेरे आरोप मात्र राजनीतिक थे, व्यक्तिगत नहीं। चंद्र शेखर जिस ढंग से पार्टी चला रहे थे और धनबाद के कोयला माफिया के प्रति नर्मी दिखा रहे थे उससे मेरा जबर्दस्त विरोध था। किंतु ये मुद्दे अब अहम नहीं रह गये। मैंने उन्हें कभी बुरा आदमी नहीं समझा। उनकी प्रतिबद्धता जग-जाहिर है। अन्य राजनीतिक नेताओं से वे कहीं अधिक लचीले हैं। पंजाब, हिंदू-मुस्लिम सवाल, पिछड़े और दलित वर्गों के अपने नजरिए में वे मेरे विचार को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे सामाजिक सिद्धांत संबंधी विचार भी समान हैं। आर्थिक सिद्धांत के बारे में कुछ मतभेद जरूर हैं, किंतु विदेश नीति के मुद्दों पर हमारे विचार एक जैसे हैं।

इस बात का कोई महत्व नहीं कि चंद्र शेखर जनता दल में बने हुए हैं। न ही यह कि वे जनता दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अस्वाभाविक मेल है—तेल और पानी जैसा। अलहदगी लाजिमी है। अच्छा हो यह (अलहदगी) अभी हो जाये, सत्ता में आने के बाद नहीं। जनता दल यदि बना रहा, तो कांग्रेस की ही मदद करेगा। यह कभी विपक्षी एकता की भावना पैदा नहीं कर सकता। वीपी सिंह कांग्रेस का विकल्प पेश करने में कतई गंभीर नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी राजीव गांधी का पद हथियाने में है। जिस तरह वे महत्वहीन भूतपूर्व कांग्रेसियों को जनता दल में भर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि विपक्ष में उनकी शिरकत अस्थायी है। वे राजीव गांधी विहीन कांग्रेस की अगुवाई करना चाहते हैं।

जनता दल में जब तक हेगड़े जैसे लोग हैं, तब तक आम लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि जनता दल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है। यदि विपक्षी एकता सर्वोपरि है, तो यह पाखंड कैसा? यह (जनता दल) कांग्रेस से भला अलग कैसे है? मैं राजनीति में मुद्दों के कारण बरकरार हूं। मेरे लिए भ्रष्टाचार वाकई एक बड़ा मसला है।

जनता पार्टी के हम सभी पांच लोग मानते हैं कि यदि विपक्ष को प्रधानमंत्री के रूप में किसी को पेश करना चाहिए, तो वे चंद्र शेखर ही हैं। यदि मैंने कोई गलती की है, तो मेरी लानत-मलामत करने का उन्हें (चंद्र शेखर को) अधिकार है। हम समान लक्ष्य के लिए एकजुट हुए हैं और हमारे साथ बने रहने की आशा है। मैं नहीं कह सकता कि चंद्र शेखर प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। इसका निर्णय तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। नेता के रूप में मेरा काम जनता को यह समझाना है कि उसे क्या करना चाहिए। यदि वह (जनता) नहीं सुनती, तो जाये भाड़ में।"

—अभय अग्रवाल

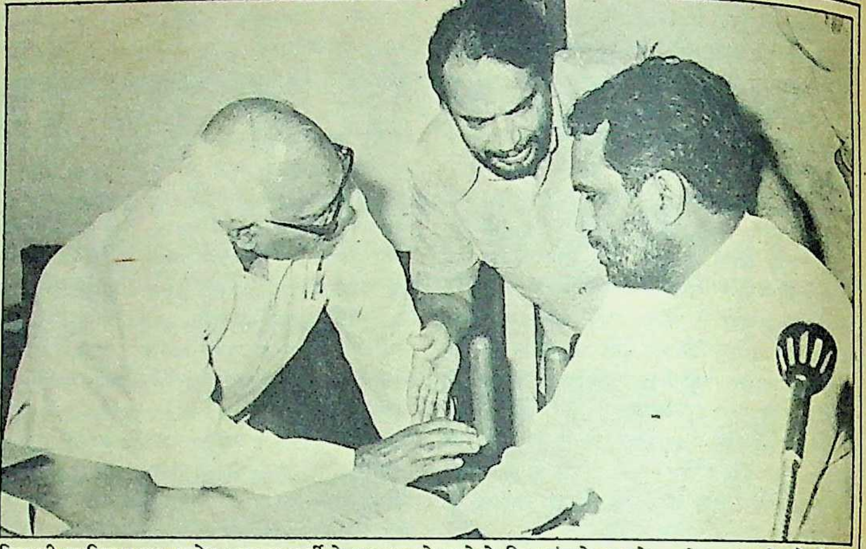

फिर भी पदलिप्सा का आरोप : जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहने के लिए चंद्र शेखर को मनाते हुए दंडवते और हेगड़े

रामकृष्ण हेगड़े भी उभरे, किंतु देवगौड़ा और अजीत सिंह की मार्फत उन्हें कर्नाटक में ही उलझाये रखा गया। बाद में जब अजीत सिंह की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गयी, तो उन्हें भी औकात बता दी गयी।" फिर स्व० हेमवती नंदन बहुगुणा की बारी आयी। थोड़ा वामपंथी झुकाव दिखाकर और वामपंथी पार्टियों से मेलजोल करके बहुगुणा को भरमा दिया गया था कि वे जनता दल के खिलाफ कड़ा स्टैंड लें। बहुगुणा और रामधन ने सोचा था कि चंद्र शेखर उनके साथ आयेंगे। लेकिन वे आये नहीं और वामपंथियों को भी लगा कि चंद्र शेखर के बिना बहुगुणा-रामधन-उन्नीकृष्णन की तिकड़ी में कोई दम नहीं है। इस अहसास के साथ उन्होंने भी इस तिकड़ी को मंझधार में छोड़ दिया।

चरमोत्कर्ष: यह लड़ाई अपने चरम पर जनवरी में ही थी जब देवी लाल अचानक चंद्र शेखर की ओर झुके और इसके साथ ही स्वामी ने वीपी सिंह पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। इसी पृष्ठभूमि में २० फरवरी के विवाद को निश्चित रूप से दो ठाकुरों की खुली लड़ाई की शुरुआत माना गया। तुरंत वीपी सिंह के समर्थक बेमन से सलाह-मशविरा करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि देवी लाल को अपनी ओर खींचने में सफल होने के बाद चंद्र शेखर अब तख्ता-पलट करने ही वाले हैं।

इस संबंध में उप्र के एक काफी उग्र जनता दल नेता कहते हैं, "राजीव गांधी की पराजय को निश्चित मानकर चंद्र शेखर यह भी सोच बैठे थे कि हर्शमैन या सरकारी एजेंसियों से आने वाले दस्तावेजों से वीपी सिंह की छवि खराब हो जायेगी। मैं यह बात खुले तौर पर इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वीपी सिंह खुद ही इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।" यह सही है कि वीपी सिंह और चंद्र शेखर में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है कि 'लड़ाई' बढ़े। चंद्र शेखर २२ फरवरी को दिल्ली से बाहर चले गये और वीपी सिंह भी उप्र और बिहार के लंबे दौरे पर निकल पड़े।

इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि देवी लाल अपनी एक साल पुरानी बात पर लौट गये हैं कि वीपी सिंह ही उनके प्रधानमंत्री होंगे। हरियाणा, उप्र और बिहार की सभाओं में देवी लाल ने एक पखवाड़े में ही यह बात तीन बार कही। इससे वह तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, जो चंद्र शेखर और वीपी सिंह समर्थकों के बीच महाभारत का रूप लेने का अंदेशा करा रहा था। लेकिन अभी सिर्फ गर्मी ही कम हुई है। शीत युद्ध तो चलेगा ही। यह तो ऐसा ही मामला है कि फौजें सीमा से पीछे आ गयी हैं, किंतु आगे लड़ाई नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।

चंद्र शेखर का दुख: शायद इसीलिए चंद्र शेखर के दो दशक पुराने सहयोगी और फिलहाल जनता दल के एक प्रमुख बौद्धिक नेता कहते हैं, "संसदीय बोर्ड की बैठक में जो कुछ हुआ उससे वे (चंद्र शेखर) दुखी हैं। मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं चंद्र शेखर को २० से अधिक वर्षों से जानता हूं और मैं वीपी सिंह को भी थोड़ा जानता

साक्षात्कार/रामकृष्ण हेगड़े

मुझे खुशी है कि सत्ता के दलालों का भंडाफोड़ हो गया

"जो लोग जनता दल की एकजुटता में बाधक हैं, यदि वे पार्टी छोड़ दें, तो कोई हानि नहीं होगी" दल के उपाध्यक्ष रामकृष्ण हेगड़े ने नर्मी से, किंतु दृढ़तापूर्वक यह बात 'माया' से कही। यह पूछने पर कि कुछ नेताओं के दल से अलग हो जाने पर का क्या हश्र होगा उनका दोटूक जवाब था कि जनता दल की शक्ति का मूलाधार कोई नेता नहीं। इसकी असली ताकत जनसमर्थन है जो आज वीपी सिंह को प्राप्त है। जनता उन्हें एक विकल्प के रूप में देख रही है। ऐसे राजनीतिक माहौल में और सब बेमानी है।

इसीलिए मैं समझता हूं कि वीपी सिंह को अपनी ताकत पहचान कर अधिक निर्णायक ढंग से काम करना चाहिए, जिससे जनता दल जन आकांक्षाओं का वाहक बन सके। उन्हें पार्टी को लामबंद करने के लिए पहलकदमी करनी चाहिए और निजी स्वार्थ-हित साधने पर उतारू लोगों द्वारा रोड़ा अटकाने और टांग खींचने की वारदातों को अनदेखा करना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि वीपी सिंह ने हरेक को साथ लेकर चलने का लोकतांत्रिक तरीका अपनाया और सबके विचारों और नामजद लोगों को स्थान दिया। किंतु इस सिलसिले के जारी रहने और जनता दल के सुदृढ़ीकरण की समस्या खड़ी होने पर उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा।"

चंद्र शेखर की जनता दल तोड़ने की धमकी पर वे बोले, "मैंने कुछ समय पूर्व चंद्र शेखर से भेंट कर पूछा था कि क्या इंदुभाई पटेल, सुब्रह्मण्यम स्वामी और अन्य ने जनता पार्टी बनाने के पूर्व आपसे सहमति ली थी? चंद्र शेखर का जवाब था, कि उन लोगों ने उनसे मुलाकात जरूर की थी। वे जनता दल में शामिल चंद ताकतों के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें जनता दल से बाहर रहने की सलाह दी थी।

ऐसा लगता है कि दल छोड़ने की बात सोचने वालों के मन में कोई वैकल्पिक आधार है। इसीलिए इसके पांच सदस्य—स्वामी, देवगौड़ा, सरोजिनी महिषी, शहाबुद्दीन व इंदु भाई—जो सबके सब चंद्र शेखर के दोस्त हैं—अपनी पार्टी को पुरानी जनता पार्टी का केंद्र बिंदु ठहराते हैं। यह उन लोगों का शरणस्थल बनेगा जो अपने सत्ता के खेल में अंततः मुंह की खायेंगे।

मुझे खुशी है कि सत्ता के दलालों का अब भंडाफोड़ हो गया है। उनका जनता दल—"में कोई स्थान या महत्व नहीं।" ■

क्या ये दिन लौटेंगे ? : पदयात्रा के समय चंद्र शेखर की लोकप्रियता

हूं। अब जब दोनों खुलेआम उलझ पड़े हैं, तो वे इस बात को भुला नहीं सकते। आंख का पानी जब उतर जाता है, तो फिर हर चीज मुमकिन है।''

इस संबंध में मोहन कुमार स्वामी बताते हैं, ''चंद्र शेखर यारों के यार हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन वे कठोर और प्रतिद्वंद्विता करने वाले भी हैं। विपक्ष में प्रमुखता पाने के उनके रास्ते में जो भी आड़े आयेगा उसे वे येन-केन-प्रकारेण हटायेंगे ही। लेकिन वे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगायेंगे। उनके आरोपों पर वैचारिक मुलम्मा जरूर रहता है।

पर यही कारण है कि जब चंद्र शेखर वीपी सिंह पर गरमा गये, तो हर किसी को अचरज हुआ। यह तो एकदम साफ निजी टकराहट थी।''

वीपी सिंह का रुख : मजे की बात यह है कि चंद्र शेखर के रुख पर वीपी सिंह ने कोई बेचैनी तो नहीं दिखाई, लेकिन यह संकेत भी नहीं दिया कि जो कुछ हुआ उसे वे भूल गये हैं। उल्लेखनीय है कि एक जनवरी १९८९ को उन्होंने घोषणा की थी कि स्वामी और पटेल जैसे लोगों के लिए जनता दल में कोई स्थान नहीं है। असल में २८ दिसंबर को उन लोगों ने जनता पार्टी के गठन की घोषणा की थी, इसी के बाद वीपी सिंह ने यह कहा था। फिर वीपी सिंह ने एनटी रामाराव और ज्योति बसु की सहमति से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, रामधन और केपी उन्नीकृष्णन की मंडली को राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष मंडल से बाहर निकाला और फरवरी के आखिर में इस विवाद और उसके दुष्परिणामों की उपेक्षा करते हुए वे जनसभाओं को संबोधित करने निकल पड़े। स्पष्ट रूप से उनकी रणनीति है कि वे चंद्र शेखर की ओर से हुए वार की उपेक्षा करें और अपना ऐसा जनाधार बनायें जो चंद्र शेखर को हमला करना बंद करने के लिए बाध्य करे।

इस बारे में 'माया' ने जब देवी लाल से पूछा, तो उनका जवाब था, ''जनता दल में कोई विवाद नहीं है। जो लोग शोर मचा रहे हैं उनमें से अधिकांश-स्वामी, पटेल, रामनरेश यादव-राज्यसभा के सदस्य हैं, जो दोबारा राज्यसभा में जाने के लिए ऐसा कर

साक्षात्कार/**कृष्णकांत**

चंद्र शेखर शुरू से वामपंथी रुझान के रहे हैं

चंद्रशेखर से मैं १९६६ में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद पहली बार मिला। मिला। हमारे एक साथ होने का कारण समान वामपंथी रुझानवाला व्यापक नजरिया था। यद्यपि हममें से किसी की कोई कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि नहीं थी। हमने इजारेदार घरानों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, जो हमारी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी, न कि इंदिरा गांधी का संकेत। मोरारजी देसाई विरोधी हमारे अभियान से श्रीमती गांधी लाभान्वित हुईं। उस समय लोग मानते थे कि हम उनके (श्रीमती गांधी) इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। १९६९ में कांग्रेस विभाजन के बाद चंद्र शेखर को प्रथम कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में नहीं लिया गया। १९७१ में कांग्रेस में शामिल कम्युनिस्टों ने श्रीमती गांधी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हमारे श्रीमती गांधी से मतभेद १९७२ में तब आरंभ हुए जब उन्होंने अर्जुन अरोड़ा को इसलिए टिकट नहीं दिया, क्योंकि वे मूलभूत परिवर्तन के हामी निर्दलीय थे।

श्रीमती गांधी दिनोदिन चंद्र शेखर से चौकन्नी होती गयीं, क्योंकि वे उन समाजवादी कार्यक्रमों को लागू करने की मांग कर रहे थे जिसे मोरारजी देसाई विरोधी संघर्ष में हम 'युवा तुर्कों' का सहयोग पाने के लिए उन्होंने (श्रीमती गांधी ने) अपनाया था। कम्युनिस्टों ने भी श्रीमती गांधी से कहा था कि वे प्रतिद्वंद्वी सत्ता केंद्र बनने में पूर्ण सक्षम हैं। मैं स्वयं तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की अगुवाई कर रहा था। जयप्रकाश नारायण के उदय के बाद हमने उनसे (श्रीमती गांधी से) बातचीत करनी चाही। क्योंकि हम किसी प्रकार के टकराव के खिलाफ थे।

किंतु श्रीमती गांधी ने आपातकाल घोषित करने के तुरंत बाद चंद्र शेखर को जेल में डाल दिया। आपातकाल के बाद उनकी (चंद्र शेखर की) वही स्थिति थी जैसी आज वीपी सिंह की है। वे अपनी महत्ता और जेपी के समर्थन के बलबूते जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गये। जेपी ने चंद्र शेखर को प्रधानमंत्री बनाने का कोई सुझाव नहीं दिया था। चंद्र शेखर की वकालत करते हुए मैंने राज्यसभा में २१ जुलाई १९७५ को कहा था कि अपने कांग्रेसी साथियों-चंद्र शेखर व रामधन-को दक्षिणपंथी षड्यंत्र से संबद्ध करना बहुत कठिन है। चंद्र शेखर शुरू से वामपंथी रुझान के मालिक और गरीबों के लिए लड़नेवालों की अगली कतार में रहे हैं...। ये दोनों साथी रातोरात दक्षिणपंथी षड्यंत्रकारी कैसे बन सकते हैं? मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें गत कुछ वर्षों के अंदर कांग्रेस के कार्यक्रम में तोड़फोड़ करने के लिए दंडित किया गया है? जवाब है केवल कृष्ण कांत, चंद्र शेखर, मोहन धारिया और रामधन। उनके जगजाहिर अपराध महज यही हैं कि वे पार्टी कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हैं और वे इसे मन, वचन और कर्म से लागू करने के लिए लगातार जोर देते आये हैं। गांधी, नेहरू और समाजवाद के लिए संकल्पबद्ध लोगों को जेल के सीखचों के भीतर डाल दिया गया है।'' ■

रहे हैं।'' यह पूछे जाने पर कि क्या चंद्र शेखर जनता दल को तोड़ देंगे ? देवी लाल ने तुरंत जवाब दिया, "मेरे मन में उनके लिए काफी सम्मान है और मैं पक्का जानता हूं कि चंद्र शेखर बहुत ही तेज राजनेता हैं। वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वे जनता दल से नहीं निकलेंगे।'' देवी लाल के स्वर में आत्मविश्वास भरा है। सच तो यह है कि चंद्र शेखर ने ही सोहना में उनसे भेंट करके उन्हें अपनी ओर किया था। पहले वे वहीं जनता दल के अन्य नेताओं से मिले थे। उन्होंने बलिया में स्वतंत्रता सेनानियों के एक सम्मेलन में आने के लिए देवी लाल को न्यौता भी दिया था।

मुलायम सिंह यादव को उप्र और लालू प्रसाद यादव को बिहार में नेता बनवाने के लिए उन्हें चंद्र शेखर के सहयोग की जरूरत भी थी। राजनीति में ऐसा आदान-प्रदान चलता रहता है। लेकिन देवी लाल यह नहीं भूल सकते हैं कि चंद्र शेखर ने हरियाणा के चुनाव के समय उनके साथ गठबंधन नहीं होने दिया था। इस संबंध में थोड़ी मुस्कुराहट के साथ देवी लाल कहते हैं, "उन लोगों ने जिन ७६ उम्मीदवारों को खड़ा किया था उन सबकी जमानतें जब्त हो गयीं।'' उनके पास बैठा एक आदमी उन्हें याद दिलाता है, "चौधरी साहब, आप वीपी सिंह, ज्योति बसु, एनटी रामाराव, रामकृष्ण हेगड़े सभी पर तो कांग्रेस ने अनेक आरोप लगाये हैं किंतु चंद्र शेखर पर १९८५ में स्वामी द्वारा लगाये गये आरोपों को छोड़ दें तो और कोई आरोप नहीं लगा है।'' इस पर देवी लाल मौन धारण कर लेते हैं।

अजीब तालमेल : इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देवी लाल जब चंद्र शेखर के करीबी थे तब भी वीपी सिंह के साथ उनका तालमेल गड़बड़ाया नहीं था। उनकी आंख का आपरेशन हुआ था इसी कारण वे बिहार के सासाराम में होने वाली सभा में (जो दो बार टली) नहीं जा पाये। हरियाणा भवन में उनको देखने आये वीपी सिंह ने कहा, "अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या मैं आपकी ओर से वहां चला जाऊं।'' इसलिए चंद्र शेखर के आलोचकों का यह अंदेशा गलत है कि उन्होंने देवी लाल के साथ कोई साठगांठ कर ली है और उनके बिना चंद्र शेखर वीपी सिंह के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे यह उम्मीद नहीं की जा सकती।

उत्तरी भारत में देवी लाल का और वीपी सिंह का काफी असर है। अपने दोस्तों से रिश्ता निभानेवाला स्वभाव रखने के बावजूद चंद्र शेखर अच्छी तरह जानते हैं कि इंदुभाई और स्वामी जैसे लोग एक भी सीट नहीं जितवा सकते। कर्नाटक में अभी भी बोम्मई सरकार टिकी हुई है। करुणानिधि, एनटी रामाराव और ज्योति बसु जनता दल के साथ हैं। ऐसे में किसी और विपक्षी नेता के लिए जगह ही कहां बचती है, भले ही वे चंद्र शेखर ही क्यों न हों।

चंद्र शेखर की उम्र ६२ वर्ष हो चुकी है। देश भर में, वह भी समृद्ध राज्यों में, फैले अपने ट्रस्टों (*देखें बाक्स*) की मार्फत वे समाज सेवा की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर चुके हैं। श्रीमती गांधी के शासन काल में युवा तुर्क नेता की हैसियत से वे किसी भी मंत्री से अधिक शक्तिशाली थे। जनता शासन काल में वे इससे बेहतर स्थिति में थे। पिछले आठ वर्षों में भी उन्होंने अपनी पहुंच और सत्ता बनाये रखी है।

सैयद शहाबुद्दीन ने तो एक बहुत ही दिलचस्प बात बतायी। वे कहते हैं, "पुरानी जनता पार्टी की अलग छवि बनाये रखने का प्रस्ताव उन्होंने स्वामी और पटेल के कहने पर तैयार किया था। दिसंबर के अंत में इसे प्रकाशित किया गया। उस समय चंद्र शेखर विदेश में थे। ९ जनवरी को जब वे वापस आये, तो मुझ पर बहुत नाराज हुए। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उन्होंने स्वामी और इंदुभाई को मना किया था कि जब तक मैं न आऊं, कुछ मत करना। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि उन लोगों ने मुझे नयी बात नहीं बतायी थी, तब उनका गुस्सा शांत हुआ।'' फिर अगले हफ्ते भर वे शहाबुद्दीन को हर तरह से मनाते-फुसलाते रहे कि वे जनता दल में शामिल हो जांयें। कहते हैं कि उन्होंने शहाबुद्दीन से कहा, "तब आपको अकेले मुझसे ही कोई मतलब नहीं है।''

चंद्र शेखर

देश के सबसे बड़े ट्रस्टी

चंद्र शेखर द्वारा नियंत्रित भारत यात्रा ट्रस्ट की भूमि का विवरण :

अगाली (केरल) : पालघाट जिले में इस ट्रस्ट के केंद्र का प्रारंभ २९ मई १९८४ को किया गया था। इस शाखा के पास कुल २५ एकड़ जमीन है।

यरकौड (तमिलनाडु) : शेवराय पहाड़ियों में स्थित इस ट्रस्ट के केंद्र के पास सात एकड़ जमीन है। इसको ११ अक्तूबर १९८३ को प्रारंभ किया गया था।

सारनाथ (उत्तर प्रदेश) : यह ट्रस्ट के उत्तर प्रदेश स्थित दो केंद्रों में से एक है। ऋषिपत्तन रोड पर स्थित इस केंद्र के पास एक एकड़ भूमि है।

आदमपुर (उत्तर प्रदेश) : देवग्राम नामक यह केंद्र भारत-नेपाल सीमा के निकट बहराइच जिले में १७ जून १९८४ से कार्य कर रहा है, इस केंद्र के पास सात एकड़ भूमि है।

परनदावाड़ी (महाराष्ट्र) : जय प्रकाश पतन नामक यह केंद्र परनदावाड़ी गांव की पहाड़ियों में स्थित है। इस केंद्र के पास २५ एकड़ भूमि है। पवना नदी के निकट स्थित इस केंद्र को दिसंबर १९८३ को प्रारंभ किया गया था।

मरालवाड़ी (कर्नाटक) : कनकपुरा तालुका के सुदूर इलाके में स्थित यह केंद्र जुलाई १९८४ में खोला गया था। इस केंद्र के अधीन १९ एकड़ भूमि है।

भौंडसी (हरियाणा) : गुड़गांव जिले में अरावली पहाड़ियों की तलहटी के भौंडसी गांव में स्थित इस केंद्र के पास ३५ एकड़ जमीन है। यह १७ अप्रैल १९८४ से काम कर रहा है।

—अ०अ०

चुनावी रणनीति के मामले में भी स्वामी और शहाबुद्दीन के दृष्टिकोण में फर्क है। स्वामी को लगता है कि वीपी सिंह का जनता दल कांग्रेस की तरह ही घटिया है, इसलिए उसके बने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर सैयद शहाबुद्दीन राजीव सरकार को पराजित करने में संयुक्त विपक्ष को मदद करने को तैयार हैं।

ऐसी स्थिति में चंद्र शेखर जनता पार्टी में रह गये इन लोगों के दम पर क्या राजनीतिक फायदे उठा पायेंगे ? निजी तौर पर भले ही वे उन लोगों को जितना चाहें, लेकिन उन लोगों के साथ वे राजनीतिक वनवास नहीं ले सकते। एक बार उन्होंने कहा भी था, "अगर हर आदमी मेरी बात सुनता, तो बहुत विवाद नहीं होते।'' उनका इशारा स्वामी अर वीपी सिंह तथा जनता दल के खिलाफ स्वामी के अभियान की ओर था। उनकी नाराजगी स्वामी से नहीं उनके तरीके से है।

छवि बिगड़ने का डर : राजनीतिक बातचीत में अक्सर चंद्र शेखर के भागीदार बननेवाले उनके एक मित्र कहते हैं, "इस घटना से चंद्र शेखर की छवि बहुत बिगड़ी है। वीपी सिंह की छवि भी कमजोर हुई, लेकिन वे इस छवि से पार पा सकते हैं। मेरे मित्र चंद्र शेखर ने खुद को एक ऐसे राजनेता के रूप में पेश किया, जो इतना अधैर्यवान है कि पार्टी को भी तोड सकता है लेकिन लोग एकता चाहते हैं। उन्होंने अपना ही बहुत नुकसान कर लिया है। मुझे इसका बहुत अफसोस है।''

बहरहाल, २० फरवरी की उबाल या लड़ाई का संकेत समय की धारा के विपरीत तो है ही। मौजूदा समय में जरूरत आपसी झगड़ों या 'इगो की टकराहट' की नहीं। जनता, कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प चाहती है। अफसोस तो इस बात का है कि भारत में मजबूत विपक्ष की संभावना छोड़ चुकी जनता का भी नेताओं को खयाल नहीं है। जनता की विश्वसनीयता हासिल करने के क्या तरीके हैं यह विपक्षी भलीभांति जानते हैं। किंतु वे उन तरीकों को अमल में तभी ला सकते हैं जब वे अपने अहम को दरकिनार रख, लोकतंत्र की रक्षा को मन से प्राथमिकता दें। बात सिर्फ एक चंद्र शेखर की उबाल की नहीं, नुकसान सिर्फ २० फरवरी की लड़ाई से ही नहीं होगा। सचाई तो यह है कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं विपक्षी एकता उतनी ही कठिन अग्नि परीक्षा से होकर गुजर रही है। जाहिर है, '७७ के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए जनता इतनी आसानी से विपक्ष पर विश्वास नहीं कर लेगी। इस बार विश्वास हासिल करने के लिए विपक्ष को फूंक-फूंककर कदम रखने होंगे। यदि २० फरवरी की पुनरावृत्ति रोकी नहीं गयी या विपक्षी नेताओं ने आपसी तालमेल नहीं बनाया, तो निस्संदेह आगामी चुनाव में भी कुछ खास परिवर्तन की आशा नहीं।

—**रंजना कक्कड़,**
त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव के साथ

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का धर्मसंकट

भाकपा ने अब एक ओर अपनी कांग्रेसपरस्त शक्ल बदल ली है, तो दूसरी ओर माकपा की 'शक्ति-प्रदर्शन' वाली राह अपना ली है। इस तरह पहचान बदलने के लिए उसे किस संकट ने मजबूर किया है? और इसके अंजाम क्या हो सकते हैं?

कैडर का कमाल: दिल्ली में माकपा की रैली

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने अपनी हाल की कलकत्ता कांग्रेस के समापन पर पांच लाख की विशाल रैली आयोजित कर यह साबित कर दिया कि 'हम भी किसी से कम नहीं।' मार्क्सवादी पार्टी (माकपा) के इस खास गढ में रैली करने का उद्देश्य समूचे देश के सम्मुख अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना तो था ही, उससे भी अधिक उस माकपा को प्रभावित और सम्मोहित करना था, जिससे अपने पुराने गिले-शिकवे ताक पर रख वह (भाकपा) हाथ मिलाने को आतुर है।

मान-मनौव्वल के इस खेल में दिलचस्प तथ्य यह रहा कि यद्यपि अल्बानिया को छोड़ ४६ देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाकपा की इस कांग्रेस में भाग लिया, किंतु माकपा गैरहाजिर रही। कारण दावतनामा न दिया जाना था। इस विडंबनापूर्ण स्थिति का कारण माकपा की गत दिसंबर-जनवरी में आयोजित त्रिवेंद्रम कांग्रेस में भाकपा को निमंत्रण न देकर पूर्णतया अनदेखा करना रहा, बावजूद इसके कि दर्जनों विदेशी बिरादराना प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस में शामिल थे। 'जैसे को तैसा' कम्युनिस्टों की चिरपरिचित रणनीति जो ठहरी।

धर्मसंकट: १९६४ के पार्टी-विभाजन के समय सबल-सक्षम भाकपा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक चौथाई शतक के पश्चात ही भविष्य को लेकर उसके सम्मुख ऐसा धर्मसंकट आ जायेगा कि अपनी कांग्रेस-समर्थक 'लाइन' बदलने के साथ ही उसे अपने से अलग हुई माकपा के रास्ते पर मजबूर होकर अग्रसर होना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि १९६७ से १९७७ तक कांग्रेस से चोली-दामन का साथ भाकपा के लिए शुरुआती दौर की सफलता के लगभग एक दशक बाद, जब केरल में कांग्रेस गठजोड़ से उसकी अगुवाई में अच्युत मेनन सरकार बनी थी, आत्मघाती सिद्ध हुआ। बिहार, उप्र, आंध्र, केरल जैसे राज्यों में जितनी तेजी से वह फली-फूली, उतनी ही तेजी से उसका ह्रास भी हुआ और इसका लाभ गया माकपा के खाते में।

मूलतः नेताओं को साथ लेकर अपना झंडा-डंडा अलग करनेवाली माकपा बड़े पैमाने पर भाकपा कार्य-कर्ताओं को भले ही अपनी ओर फोड़ने में सफल न रही हो, किंतु नये प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ाने में उसे अवश्य कामयाबी हासिल हुई। आज तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा, में उसके न केवल मजबूत दुर्ग हैं, बल्कि प्रथम दो में वामपंथी साझा-सरकारों में उसके अपने मुख्यमंत्री भी हैं। किसी राज्य में वर्चस्व स्थापित करना तो दरकिनार, इसी दौरान भाकपा के अनेक पारंपरिक गढ़ भी चकनाचूर हो गये। हानि-लाभ के इस जगजाहिर राजनीतिक परिदृश्य में भाकपा का आत्ममंथन कर नयी रणनीति बनाना अस्वाभाविक नहीं था। सी राजेश्वर राव ने कलकत्ता कांग्रेस के समापन पर इस भावी रणंनीति की व्याख्या करते हुए चुनावी वर्ष की तीन प्राथमिकताएं—कांग्रेस को हटाना, विपक्ष को भाजपा से अलग रखना और वामपंथी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करना—तो अवश्य गिनाईं, किंतु इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम पेश करने में पार्टी असफल रही, जबकि इसके लिए निर्णय १९८७ में ही ले लिया गया था। किंतु जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया, वह न तो माकपा को संतुष्ट कर सका न प्रतिनिधियों को। संशोधन के लिए २०० से अधिक प्रस्तावों का जो अंबार लगा, वह अलग। मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा कि ठोस कार्यक्रम तय करने के लिए एक विशेष कांग्रेस बुलाई जायेगी। इस फैसले के पीछे पर्यवेक्षक चुनाव पूर्व सभी विकल्प खुले रखने की रणनीति देख रहे हैं।

भाजपा महासचिव किशनलाल शर्मा के अनुसार, "भाकपा में असुरक्षा की भावना घर कर गयी है। इसका प्रमुख कारण उसकी ढुलमुल नीतियां हैं, जिनके चलते उसका जनाधार भी घटा है। अर्से तक कांग्रेस समर्थक होने के कारण भाकपा आज भी अपनी कालिमा धो पाने में असमर्थ है। फलस्वरूप उसे लेकर विपक्ष में संदेह-संशय होना स्वाभाविक है।"

एक जैसी स्थिति: यही संशय-संदेह माकपा में भी है। उल्लेखनीय है कि भाकपा कांग्रेस ने वामपंथी पार्टियों की एकता और विलय का जो आह्वान किया उसके जवाब में ठीक ४८ घंटे बाद माकपा के बंगला मुखपत्र 'गणशक्ति' ने भाकपा को प्रति क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी करार दिया। यह कदाचित बिहार के भाकपा नेता और पार्टी सचिवमंडल के नये सचिव चतुरानन मिश्र की इस टिप्पणी का जवाबी हमला था, "हम ज्योति बसु को दादा तो मान सकते हैं, किंतु उनकी दादागिरी को नहीं।"

जहां तक भाकपा-माकपा की एकजुटता का सवाल है, महासचिव राजेश्वर राव ने 'माया' को एक विशेष भेंट में बताया, "भाकपा अपने अस्तित्व को लेकर नहीं, बल्कि देश के संगीन हालात को लेकर चिंतित है। हमारा मानना है कि जब वामपंथी दलों में एकता होगी तभी वे प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा सकेंगे। हम यह कभी नहीं मानते कि कोई एक वामपंथी पार्टी देश को संभाल सकती है।"

भाकपा यह भी नहीं स्वीकारती कि माकपा से हाथ मिलाने के लिए वह झुकी है अथवा हाल में उसने कोई लाइन बदली है। पार्टी सचिव एम फारूकी के अनुसार "वामपंथी एकता की जो बात आज हम कर रहे हैं उसका कारण यह है कि अहम् राष्टीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे विचार लगभग समान हो गये हैं। हाल में भाकपा ने लाइन बदली है। हमने जो लाइन बदली थी वह १९७८ में आपातकाल के अपने समर्थन की गलती को समझते-स्वीकारते हुए। हममें और माकपा में फर्क यह है कि हमने लाइन बदलने की बात खुलेआम स्वीकार की है और उन्होंने नहीं।"

राय जुदा-जुदा: इसके ठीक विपरीत राय माकपा महासचिव ईएमएस नंबूदिरीपाद की है। उनके अनुसार, "भाकपा कम्युनिस्ट पार्टियों को

विलय के पूर्व वामपंथी राजनीति को सुदृढ़ करने की नीति अपनाये।'' नंबूदिरीपाद का आरोप है कि भाकपा तमिलनाडु में द्रमुक और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के विरोध की जो राजनीति कर रही है उससे विपक्षी राष्ट्रीय मोर्चे को कमजोर बना रही है। इसके जवाब में कामरेड राजेश्वर राव का कहना है, ''आंध्र के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की नीतियां कांग्रेस से भी गयी-बीती हैं। स्पष्ट कहा जाये, तो वहां उनकी तानाशाही कायम है। यह कहां का लोकतंत्र है, जहां एक झटके में सभी ३१ मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाता है? हम अपने हित-लाभ के लिए क्या गैरकांग्रेस और गैरवामपंथी सरकार के सारे खून माफ कर दें?''

भाजपा के प्रश्न पर भी दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों में मतभेद रहा है, किंतु दोनों ने अपना-अपना रवैया भी बदला है। माकपा ने जहां भाजपा को पहले अछूत करार दिया था, वहीं अब उसे लेकर पार्टी में दो स्पष्ट खेमे बन गये हैं। नंबूदिरीपाद पूर्ण विरोध कर जनता दल व भाजपा में किसी प्रकार के समझौते की रोकथाम में लगे हैं, तो ज्योति बसु को जनता दल-भाजपा तालमेल से परहेज नहीं। भाकपा भी इस मुद्दे पर एकराय नजर नहीं आती। पार्टी का बहुसंख्य वर्ग भाजपा को कांग्रेस से बड़ा दुश्मन मानते हुए उसे सांप्रदायिकता का जहर घोलनेवाला और देश की एकता-अखंडता को खतरे में डालनेवाला करार देता है। इसके चलते इस खेमे को जनता दल-भाजपा समझौते से भी परहेज है। इसके ठीक विपरीत मत भाकपा उपमहासचिव इंद्रजीत गुप्त का है। उनका मानना है, ''जनता दल और दूसरे दल यदि भाजपा से चुनावी तालमेल कर ही लेते हैं, तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं।''

असलियत : दिलचस्प तथ्य यह है कि लगभग दो वर्ष पूर्व के हरियाणा विधान सभा चुनावों के दौरान दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने उस लोकदल से समझौता किया था जिसने न केवल भाजपा से चुनावी गठबंधन ही किया था, बल्कि आज उसके साथ मिलकर साझा सरकार भी चला रहा है। जब इसकी चर्चा भाकपा सचिव एम फारूकी से चली, तो उन्होंने कहा, ''हम किसी बूर्जुवा पार्टी के फैसले से बंधे नहीं हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में लोकदल से तालमेल के बावजूद हमने ७ स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़े किये थे।''

गले की हड्डी : ऐन करीब लोकसभा चुनावों में तालमेल का प्रश्न भाकपा के लिए गले की हड्डी बन गया है। माकपा से तालमेल के बिना वह उसके प्रभाव क्षेत्रों-पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा आदि में अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर सकती। साथ ही हिंदीभाषी क्षेत्रों-बिहार, उप्र, पंजाब आदि में अगर वह भाजपा से सहयोग के प्रश्न पर जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे से अपने को अलग-थलग रखती है, तो उसका जो थोड़ा-बहुत जनाधार है उसमें भी कमी होने की आशंका है।

विरोध-नीति के विरुद्ध : नंबूदिरी पाद

पेशकश पर चुप्पी : इंद्रजीत गुप्त और ज्योति बसु

चुनाव करीब होने से उसकी रणनीति में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि उच्च नेतृत्व में तब्दीली के पूर्व फैसले को भी ताक पर रख दिया गया है। ज्ञात रहे कि कुछ समय पूर्व ही उपमहासचिव इंद्रजीत गुप्त को आगामी कलकत्ता कांग्रेस में पार्टी महासचिव बनाने का निर्णय लिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार पार्टी उपमहासचिव इंद्रजीत गुप्त की तटस्थता-निष्पक्षता पर आंध्र-लाइन वाले पार्टीजनों ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया, क्योंकि वे कुछ मुद्दों पर केंद्रीय लाइन के पक्षधरों का समर्थन करते पाये गये थे। ज्ञात रहे कि बूर्जुवा पार्टी से तालमेल को लेकर केंद्र तथा आंध्र दोनों लाइनों में भारी मतभेद रहा है। आंध्र लाइन के पक्षधर किसी दल पर आश्रित न होने के अधिक समर्थन-प्रचारक रहे हैं, तो केंद्रीय लाइन वाले विपक्षी तालमेल के। जानकार सूत्रों के अनुसार चल रहे इस विवाद के कारण ही इस समय यथास्थिति बनाये रखने के लिए सी॰ राजेश्वर राव को महासचिव बनाये रखना लाजिमी समझा गया। जब 'माया' ने इस बारे में राजेश्वर राव से पूछा तो उन्होंने कहा, ''पार्टी में नवीनीकरण और नये खून का संचार हो—यह फैसला बरकरार है। इसी के चलते राष्ट्रीय परिषद, केंद्रीय कार्यकारिणी और सचिवमंडल में अनेक नये चेहरे देखे जा सकते हैं। बात महासचिव को बदलने की अवश्य थी, क्योंकि मैं इतने वर्ष इस पद पर बना रहा हूं, किंतु अंतिम क्षणों में इस पर अमल रोक दिया गया। कारण, अधिकांश लोगों ने सोचा कि इस तब्दीली का लोग अलग-अलग मतलब निकालेंगे, जो मौजूदा चुनावी वर्ष में ठीक नहीं होगा। उपमहासचिव और मेरे बीच पूरा तालमेल है और इस पर आपसी समझदारी भी कि पार्टी में समय-समय पर तब्दीली होगी, जिसमें महासचिव का पद भी शामिल है।''

जरूरत : भाकपा के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव से अधिक प्रभाव कदाचित उसके भावी कार्यक्रमों, रणनीतियों और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की एकता पर पड़ेगा। इनमें से प्रथम दो तो भाकपा के वश में है, किंतु तीसरे का फैसला माकपा के हाथ में है जो 'वेट एंड वाच' की अपनी कूटनीति के तहत भाकपा के एक-एक कदम की नापजोख कर रही है। माकपा भाकपा से विलय के लिए यदि राजी भी होगी, तो निश्चित ही अपनी शर्तों पर। आत्मरक्षा और आत्मसम्मान-भाकपा के सामने ये दोनों प्रश्न आज भयावह रूप से रूबरू है। क्या दोनों पार्टियां कम्युनिस्ट एकता और विलय के लिए कोई ऐसा कारगर रास्ता निकाल पायेंगी जिसकी बाट साम्यवादी दशकों से जोह रहे हैं?

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ,

फिर से साथ होने की ललक: प्रकाश सिंह बादल (बायें) और सुरजीत सिंह बरनाला

अकाली एकता

जोरदार पहल विफल क्यों ?

केंद्र सरकार द्वारा पंजाब समस्या के हल तथा पंजाब में कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए अपनायी गयी रणनीति को विभिन्न गुटों में बंटे अकाली दल ने गंभीरता से लिया तथा पंजाब में कांग्रेस के पैर न जमने देने के उद्देश्य से आपसी एकता का प्रयास शुरू किया। ११ मार्च को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो तीनों गुटों के विलय की घोषणा भी कर दी। किंतु अचानक ऐसा क्या हुआ कि विलय की ओर बढ़ते गुटों ने अपने पांव वापस खींच लिये ?

एकता के लिए की जानेवाली अकालियों की बातचीत साझा बाजार में ग्राहक को आकर्षित करने के लिए लगायी जा रही दलाल की बोली की तरह मालूम पड़ती है, जहां हर धड़ा अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आज अकाली दल के तीन घटक हैं, अकाली दल (लोंगोवाल), अकाली दल (मान), अकाली दल (तलवंडी)। जब दो घटक एकता की बात करते हैं, तब तीसरा इससे अलग रहता है। अगर विभिन्न धड़ों के वरिष्ठ नेता एक होने की सोचते हैं, तो छोटे नेताओं को एक बड़े दल में अपनी कुरसी खतरे में दिखायी देती है, जिस पर वे अपने घटक में बने हुए हैं। अतः वे इसका विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में अकाली एकता की स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है ?

असल में जहां तक अकाली एकता के नवीनतम जोरदार प्रयास के शुरू होने की बात है, तो यह कहना गलत न होगा कि हाल में केंद्र द्वारा पंजाब के लिए दिखायी गयी उदारता ने अकालियों को एकता प्रयास के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में एक राजनीतिक का कहना है कि केंद्र के पैकेज ने पंजाब में राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित

करने का काम किया। केंद्र की इस पहल के समकक्ष आखिर अकालियों को भी तो कुछ करना था। अतः तीनों धड़ों को आपसी एकता के अतिरिक्त अन्य कुछ नजर नहीं आया। नतीजतन तीनों धड़े एकता की दिशा में बढ़ने लगे । शुरू में बरनाला और तलवंडी ने काफी तत्परता दिखायी। इसीलिए बरनाला ने अपने पूर्व मंत्री बलवंत सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया जिससे कि बादल धड़ा उनके धड़े को स्वीकार कर ले, क्योंकि बार-बार अपनी निष्ठा परिवर्तन करने के कारण बलवंत सिंह बादल को पसंद नहीं हैं।

जोरदार पहल: इसमें शक नहीं कि एकता की सबसे नयी तथा जोरदार पहल कैप्टन अमरिंदर सिंह की रही। किंतु इसका भी वही हश्र हुआ, जो इससे पहले अन्य प्रयत्नों का हुआ था। ११ मार्च को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की, "अकाली दल के तीनों धड़ों—मान, तलवंडी तथा लोंगोवाल ने एक होकर शिरोमणि अकाली दल के नाम से नया दल बना लिया है। सिमरनजीत सिंह मान इस दल के संरक्षक तथा जगदेव सिंह तलवंडी इसके अध्यक्ष होंगे। समझौते में निश्चित हुआ है कि मान नजरबंद होने के कारण राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले सकते अतः नजरबंदी से छूटने के बाद वे दल के अध्यक्ष होंगे।"

अमरिंदर सिंह द्वारा अचानक अकाली एकता का प्रयास शुरू किये जाने के बारे में बताया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब २२ नवंबर को मान से मिले थे, तो उन्होंने (मान) इच्छा प्रकट की कि दल के तीनों धड़े जितनी जल्दी एक हो जायें, पंजाब समस्या के हल के लिए यह उतना ही अच्छा साबित होगा। उसी समय अमरिंदर ने मान से यह कहा था कि उनकी नजरबंदी के कारण उन्हें

जीएस तोहड़ा

बलवंत सिंह

बादल, मान तथा तोहड़ा जैसे नेता जेल में हैं। सोने पर सुहागा यह है कि धार्मिक बाने में हिंसक गतिविधियों में लिप्त आतंकवादी आज भी राज्य की लगाम थामे हुए हैं। ऐसी स्थिति में केवल ईश्वर ही जानता है कि पंजाब का कल कैसा होगा?

बरनाला ने अपने पूर्व मंत्री बलवंत सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया जिससे कि बादल धड़ा उनके धड़े को स्वीकार कर ले, क्योंकि बार-बार अपनी निष्ठा परिवर्तन करने के कारण बलवंत सिंह बादल को पसंद नहीं हैं।

साक्षात्कार/सुरजीत सिंह बरनाला

पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं

माया: *एकता के लिए अचानक यह प्रयास तथा इसके तत्काल बाद अरुचि आखिर क्यों?*

सुरजीत सिंह बरनाला: एकता के लिए मेरी पहल आकस्मिक नहीं थी। मुझे अपने पार्टी के सहकर्मियों पर दवाब डालना पड़ा था कि दूसरे धड़ों के साथ एकता को आगे बढ़ाया जाये। इस प्रक्रिया में समय लगा। जहां तक विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद पीछे हटने की बात है, तो अकाली दल (मान) के बाबा जोगिंदर सिंह घटक के तीखे विरोध तथा तलवंडी एवं कैप्टन अमरिंदर पर आपत्ति के बाद इससे पीछे हट जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। फार्मूला व्यावहारिक था, किंतु या तो अमरिंदर सिंह ने मान की तरफ से स्वयं हस्ताक्षर किये होते या बाबा जोगिंदर जैसे नेताओं की सहमति ली होती।

माया: *अफवाहें हैं कि आप अपनी पत्नी की सलाह पर आम चुनाव नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि तब आप सौदेबाजी करने की बढ़िया स्थिति में होंगे?।*

बरनाला: यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अकाली दल के उद्देश्य (लक्ष्य) पर आगे बढ़ रहा हूं और मैं ऐसा करता रहूंगा।

माया: *अकाली दल का भविष्य क्या है?*

बरनाला: हमें एकता की राह में आनेवाली बाधाओं को दूर करना होगा। मैं विभिन्न अकाली धड़ों के सामान्य कार्यकर्ताओं पर दबाव डालूंगा कि किसी भी कीमत पर एकता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जरूरी है। हमें आशा है कि केंद्र हमारे शीर्ष नेताओं को नजरबंदी से जल्द ही छोड़ देगा।

माया: *क्या तलवंडी के साथ विलय के लिए आपको कोई पद देने के लिए कहा गया था?*

बरनाला: मैंने बिना शर्त विलय किया था। ◆

असल में जहां तक अकाली एकता के नवीनतम जोरदार प्रयास के शुरू होने की बात है, तो यह कहना गलत न होगा कि हाल में केंद्र द्वारा पंजाब के लिए दिखायी गयी उदारता ने अकालियों को एकता प्रयास के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में एक राजनीतिक का कहना है कि केंद्र के पैकेज ने पंजाब में राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने का काम किया।

फिलहाल अध्यक्ष पद नहीं दिया जा सकता, अतः संरक्षक पद दिया जायेगा। अमरिंदर का कहना है कि मान इस तरह की व्यवस्था के लिए तैयार थे। अमरिंदर ने मान की इच्छा तलवंडी को बतायी, जिन्होंने इसकी प्रशंसा की। हालांकि बरनाला ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। बाद में बरनाला समर्थकों ने अमरिंदर को बताया कि बरनाला अकाली एकता के पक्ष में हैं तथा वे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस समय अमरिंदर ने एकता की पूर्व शर्तों के रूप में तीन मुद्दे उनके सामने रखे थे:

- मान नये अकाली दल के संरक्षक होंगे।
- तलवंडी इसके अध्यक्ष होंगे।
- बरनाला को बिना किसी पूर्व शर्त के अपने दल का विलय करना होगा।

मजे की बात यह कि बरनाला इस फार्मूले पर भी राजी हो गये और उन्होंने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिये। इसके बाद ही ११ मार्च को अमरिंदर ने जालंधर में पत्रकारों को यह समाचार दिया था।

निराशा : किंतु एकता का यह नवीनतम प्रयास भी स्थायी न रह सका। हालांकि अकाली एकता की संभावना तथा उसके नतीजों पर समाचार-पत्रों ने गतिविधियों को देखते हुए काफी प्रकाश डाला था तथा एकता की सराहना भी की थी, किंतु आपसी कलह तथा नेतृत्व अपने हाथ में रखने की चाह ने अकाली एकता को पुनः दोराहे पर ला खड़ा किया। इस संबंध में पर्यवेक्षकों का कहना है कि पंजाब की राजनीति का यह दुर्भाग्य रहा है कि अकाली हमेशा से, मास्टर तारा सिंह के समय से ही, जब संत फतेहसिंह को अलग कर दिया गया था, विभाजित रहे हैं। यही नहीं, कुछ वर्ष पहले जब जगदेव सिंह तलवंडी ने एकता के लिए रास्ता निकालना चाहा था, तो उस समय भी फूट सामने आयी थी और अकाली दल टुकड़ों में बंट गया था।

असम में हुआ यह कि विलय के कुछ ही घंटे बाद मान तथा बाबा जोगिंदर सिंह के नेतृत्ववाले दोनों धड़ों के सदस्यों ने अमरिंदर सिंह पर केंद्र के इशारे पर पंथिक हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने एकता प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार अमरिंदर को नजरबंद नेता सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से बोलने का कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में जब 'माया' ने अमरिंदर सिंह से असलियत जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया, "मैंने सिमरन को विश्वास में लिया था। एकता प्रयास उनकी इच्छानुसार ही था।" स्थिति देखते-देखते बिगड़ी कि अकाली दल (मान) की स्थायी समिति ने अपने दो दिवसीय सम्मेलन में कैप्टन की घोषणा को 'गुमराह करने वाली, हास्यास्पद तथा आधारहीन' बताया और इस बात की घोषणा की कि मान का अमरिंदर सिंह के एकता प्रयास से कुछ लेना-देना नहीं। यही नहीं, सुच्चा सिंह छोटपुर की मान से सात मार्च को अदालत में मुलाकात हुई थी। उनका कहना है, "दल के संरक्षक बनने के प्रस्ताव को मान द्वारा स्वीकार किये जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मान को दमदमी टकसाल का आशीर्वाद प्राप्त है तथा वे गत जनवरी में दो वर्ष के लिए दल के अध्यक्ष बनाये जा चुके हैं।" जबकि अमरिंदर कहते हैं, "कुछ भी हो मेरा और मान का उद्देश्य एकता को आगे बढ़ाना है। हमारे एक न होने पर कांग्रेस-इ लाभान्वित होगी। इंका इस वर्ष राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। यदि अकाली एक न हुए, तो बहुत संभावना है कि वह पुनः सत्ता में आ जाये।"

कांग्रेसी साजिश : किंतु अफसोस इस बात पर है कि अमरिंदर को 'झूठा' तथा 'कांग्रेस की कठपुतली' कहकर पुकारा गया। पंजाब के एक माकपा नेता का इस संबंध में कहना है, "अमरिंदर को कांग्रेस-इ की कठपुतली कैसे कहा जा सकता है,

साक्षात्कार/**कैप्टन अमरिंदर सिंह**

अकाली एकता के प्रयास के लिए मैं हाजिर हूं

माया : *अकाली एकता पर कब और कैसे विचार किया गया?*

अमरिंदर सिंह : मैं नवंबर '८८ में मान से भागलपुर में मिला था। उन्होंने मुझे एकता का प्रयास करने के लिए अधीकृत किया था। उन्होंने विशेष रूप से यह कहा था कि उन्हें संरक्षक बनने से ऐतराज नहीं, यदि इससे एकता में सहायता मिलती है। उन्होंने पंजाब की स्थिति पर विस्तार से बातें की थीं तथा तलवंडी को अध्यक्ष मानने को राजी हो गये थे। बाद में तलवंडी ने भी इस प्रस्ताव को पूरा समर्थन देने को कहा था तथा घोषणा की थी कि मान के जेल से छूट कर आते ही वे अध्यक्ष पद उन्हें (मान) सौंप देंगे। वहां से आकर मैंने मान के एकता फार्मूले को प्रचारित करना शुरू किया, किंतु बरनाला ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। १० मार्च को बरनाला ने मुझे चायल बुलाया तथा कहा कि वे (बरनाला) अपने अकाली दल का शिरोमणि अकाली दल में विलय करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने दूसरे अकाली धड़ों से भी एकता प्रस्ताव स्वीकार किया। तलवंडी को इस सारी प्रगति से दो-चार कराया गया। मैंने अकाली विलय की घोषणा पत्रकारों के सामने कर दी। इसे पंजाब का या हमारा दुर्भाग्य माना जाये कि सारे प्रयास असफल हुए तथा असफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला।

माया : *एकता प्रयास का यह हश्र क्यों हुआ?*

सिंह : अकाली दल में कांग्रेस ने अपने घुसपैठिये बिठा दिये हैं। ये लोग अकालियों को छिन्न-भिन्न रखने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। फिर स्वयं अकाली भी अपने दुश्मन हैं। कुछ नेता, जो अपने धड़ों में उच्च पदों पर बने हुए हैं, आशंकित हैं कि बड़े दल में इन सारे लोगों को उच्च पदों पर बिठा पाना संभव नहीं होगा। अतः वे अकाली एकता को अस्त-व्यस्त बनाये रखने के प्रयास में लगे हैं।

माया : *इस आरोप के विषय में आप क्या कहेंगे कि आप केंद्र की कठपुतली हैं?*

सिंह : मैं ऐसे कपटपूर्ण वक्तव्यों की परवाह नहीं करता। १९८४ में आपरेशन ब्ल्यू स्टार के समय कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही मैंने उन्हें झेला है। यदि मैं अकालियों की एकता करा दूं, तो यह केंद्र के लिए चिंता का, न कि उल्लास का विषय होगा। अतः इस तरह के आरोप तर्कहीन हैं।

माया : *पंजाब के लिए आदर्श मुख्यमंत्री आपके विचार से कौन होगा?*

सिंह : मुख्यमंत्री के रूप में बादल तथा अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में सिमरन पंजाब के लिए आदर्श सिद्ध होंगे। मैं उनका समर्थन करूंगा। अकाली एकता के किसी भी प्रयास के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। ◆

एकता के पक्षधर: बायें से दूसरे कै० अमरिंदर सिंह तथा तीसरे सुरजीत सिंह बरनाला

जबकि वह अकाली दल की एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं? इंका तो इसके विपरीत विच्छिन्न अकाली दल चाहती है।"

असल में मामला यह है कि अमरिंदर के एकता फार्मूले का मान धड़े के कुछ सदस्यों ने तो स्वागत किया था, किंतु कुछ लोगों को फार्मूला पसंद नहीं था। अमरिंदर द्वारा एकता फार्मूला पेश किये जाने के बाद शर्तों पर विचार-विमर्श करके बरनाला ने एकता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया और नागपुर चले गये थे। किंतु जब बरनाला नागपुर से वापस आये, तो उन्हें खबर मिली कि मान धड़े की तरह ही उनके धड़े के कुछ लोग भी अमरिंदर फार्मूले से संतुष्ट नहीं हैं।

स्थिति यह थी कि उनके धड़े के कार्यकारी अध्यक्ष तोता सिंह ने भी एकता के इस प्रयास में बाधा डाली थी। स्थिति का जायजा लेने के बाद बरनाला ने घोषणा की, "मैं एकता के प्रति प्रतिबद्ध रहा। मैंने ही सबसे पहले इस फार्मूले पर हस्ताक्षर किये थे। लेकिन अकाली दल (मान) के बाबा जोगिंदर सिंह गुट द्वारा अमरिंदर तथा तलवंडी पर ऐतराज किये जाने पर मेरे पास एकता प्रयास से पीछे हट जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि फार्मूला अत्यंत व्यावहारिक था तथा अमरिंदर ने तीनों गुटों की रजामंदी भी ले ली थी।" बरनाला के अनुसार, "अमरिंदर को चाहिए था कि वे इस पर मान की जगह स्वयं हस्ताक्षर करते तथा बाबा जोगिंदर सिंह के गुट के नेताओं की इस पर रजामंदी लेते। एकता दो गुटों के बीच नहीं, बल्कि तीनों गुटों के बीच होनी चाहिए थी।" जबकि अकाली दल (लोंगोवाल) के ही कुछ जानकार सूत्र बताते हैं, "बरनाला एकता प्रयासों की अपेक्षा करने लगे थे, क्योंकि उन्हें सलाह दी गयी थी कि यदि चुनाव निकट होने पर एकता होगी, तो वे बढ़िया सौदा करने की स्थिति में होंगे।"

बहरहाल, अकाली धड़ों की एकता के प्रयास और उसकी विफलता को यदि मद्देनजर रखा जाये, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एकता प्रयास में बाधा बनकर अकाली धड़ों ने पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस के लिए जगह खाली रख छोड़ी है। मौजूदा समय में अकाली गुटों की एकता की जो स्थिति है, उसे देखकर यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अकाली एकता फिर वहीं पहुंच गयी है, जहां से शुरू हुई थी। अर्थात अकाली राजनीति पुन: चौराहे पर आ खड़ी है। केंद्र की पंजाब से छेड़छाड़ भी जारी है। अकाली पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गये हैं। किसी समय निर्णायक तथा प्रामाणिक रहा अकाल तख्त आज पूरी तरह अकर्मण्य हो गया है। बादल, मान तथा तोहड़ा जैसे नेता जेल में हैं। सोने पर सुहागा यह है कि धार्मिक बाने में हिंसक गतिविधियों में लिप्त आतंकवादी आज भी राज्य की लगाम थामे हुए हैं। ऐसी स्थिति में केवल ईश्वर ही जानता है कि पंजाब का कल कैसा होगा?

फिर भी अकाली धड़ों के पल-पल बदलते रवैये तथा बयानों को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों को विश्वास है कि आज भले ही अकाली एकता ताक पर पड़ी है, किंतु जल्द ही अकाली गुट एक होंगे और पंजाब की सत्ता हासिल करेंगे। तब पंजाबवासियों को पता चलेगा कि अकाली एकता वास्तव में राजनीतिक, धार्मिक अथवा सामाजिक एकता नहीं, अपितु 'सुविधा' भोगने के लिए महज एक नातेदारी है।

—**विशेष प्रतिनिधि**

> **फिर भी अकाली धड़ों के पल-पल बदलते रवैये तथा बयानों को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों को विश्वास है कि आज भले ही अकाली एकता ताक पर पड़ी है, किंतु जल्द ही अकाली गुट एक होंगे और पंजाब की सत्ता हासिल करेंगे।**

आयुर्वेदका अणमोल उपहार!

कब्ज - आम्लपित्त के लिए लोगं जीलेक्स क्यों पसंद करने लगे

- पेट में बिना दर्द दस्त साफ।
- स्थायी आदत नहीं पड्ती।
  व्यर्थ प्रभाव नहीं पड्ता।
  नारंगी और नींबू के मीठे स्वाद में, कड्डुवाहट या तीतापन नहीं होता।
- विदेशीयों की विश्वसनीय
  जीलेक्स कुदरती है सत-ईसबगोल से बनती है।
  लेने की रीति: एक या दो चम्मच पानी के साथ ले बाद में एक ग्लास पानी पीना जरुरी है।
- स्फुर्तिभरे दिन के लिए जीलेक्स अपनाइये।

जीलेक्स
(सत-ईसबगोल की हर्बल बनावट)

आम्लपित्त, कब्ज, तजागरमी, मुहासे, हरस, मसा के लिए निर्दोष हर्बल उपचार

उत्पादक: ऊँझा फोर्म्युलेशन्स
बिंदु सरोवर रोड, सिद्धपुर ३८४ १५१
(उ.गु.) फोन ९०९, ११४

ठक्कर रिपोर्ट

राजीव सरकार के गले में एक और फंदा

साढ़े चार साल बाद आरके धवन के सत्ता-केंद्र में पुनः प्रतिष्ठित होते ही श्रीमती गांधी की हत्या की जांच के लिए नियुक्त ठक्कर आयोग की गुप्त रिपोर्ट अचानक लीक हो गयी। विपक्ष ने एकजुट होकर संसद में आक्रामक मांग की कि सरकार रिपोर्ट को सदन में पेश करे। गृहमंत्री बूटा सिंह और संसदीय मामलों के मंत्री हरकिशन लाल भगत ने जनहित और राष्ट्रहित का पिटापिटाया वास्ता देकर रिपोर्ट को पेश न करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। तीन दिन संसद में चले महाभारत के बाद अचानक १७ मार्च को प्रधानमंत्री लोकसभा में नमूदार हुए और मुनादी की कि २७ मार्च को रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी। जब रिपोर्ट पेश हुई, तो हंगामा थमने के बजाय और उग्र हो गया। इस घटनाक्रम के संदर्भ में ये सवाल अभी अनुत्तरित हैं:

- इस रिपोर्ट को अभी तक गुप्त रखने का औचित्य क्या था?
- यह रिपोर्ट किसने लीक की?
- लीक करने का उद्देश्य धवन को संकट में डालना था या स्वयं राजीव को?
- अचानक राजीव गांधी को रिपोर्ट पेश करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा?
- रिपोर्ट अधूरी पेश क्यों की गयी?
- धवन पर न्यायमूर्ति ठक्कर को यह शक किस आधार पर हुआ कि वे षड्यंत्र में शामिल थे?
- न्यायमूर्ति ठक्कर की नजर में संदिग्ध धवन को पुलिस अधिकारी आनंदराम की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल ने किस आधार पर निर्दोष माना?
- बोफोर्स के बाद क्या यह रिपोर्ट चुनाव वर्ष में सरकार के गले में एक और फंदा सिद्ध होगी?

'माया' ने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशा है:

इंदिरा गांधी हत्याकांड संबंधी ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को पेश करने के बाद भी संदेह, षड्यंत्र और रहस्य का घटाटोप छंटने के बजाय और गहराया है। रिपोर्ट को देशहित और जनहित के नाम पर अब तक गोपनीय बनाये रखने की दलील भी बेदम साबित हुई है, क्योंकि सदन में पेश रिपोर्ट का कोई भी अंश ऐसा नहीं जिससे इन हितों को क्षति पहुंचे। यही नहीं, रिपोर्ट को सार्वजनिक बनाने का ऐलान करते समय घोषित किया गया उद्देश्य—विशेषकर अटकलों, अफवाहों पर लगाम लगाना—भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अफवाहों, अटकलों, आरोपों-प्रत्यारोपों का बाजार निरंतर गर्म होता रहा है। नतीजतन संदेह की सुई, जो कल तक मात्र आरके धवन पर टिकी हुई थी, आज अन्य नामी-गिरामी हस्तियों की ओर भी सरकती नजर आ रही है।

एमपी ठक्कर   छाया: कालएस गिरोटा

इसका मूल कारण है, सरकार का किसी एक घोषणा, किसी एक निर्णय पर न टिकना। गृहमंत्री तीन दिन पहले जो बयान देते हैं, उसको तीन दिन बाद स्वयं प्रधानमंत्री बिलकुल उलट देते हैं। १७ मार्च को जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ऐलान किया कि २७ मार्च को ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी, तो इसने देश और विपक्षी राजनेताओं को ही नहीं, स्वयं कांग्रेसियों को भी स्तब्ध कर दिया, क्योंकि १४ मार्च से विपक्ष के साथ छिड़े घमासान में रिपोर्ट को किसी हाल उजागर न करने का सरकार का रवैया न केवल दो-टूक था, बल्कि अड़ियल भी था। गृहमंत्री बूटा सिंह और सूचना प्रसारण एवं संसदीय मामलों के मंत्री हरकिशन लाल भगत सीना तानकर कह रहे थे कि रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों की घोषणाओं के विपरीत रिपोर्ट पेश करने की मुनादी कर दी। राजीव गांधी ने सोचा था कि इससे विपक्ष निहत्था हो जायेगा और उसके आक्रमण की हवा निकल जायेगी। लेकिन पासा उलटा पड़ा, क्योंकि रिपोर्ट अधूरी पेश की गयी। पांच हिस्सों में से दो को ही पेश हुए।

ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में पूर्ण रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन तो दिया ही था, साथ ही जब जनता दल अध्यक्ष वीपी सिंह ने दस दिनों के अंतराल में रिपोर्ट में हेरफेर की आशंका प्रकट की, तो प्रधानमंत्री ने न केवल पूर्ण रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन ही दोहराया, बल्कि उसमें किसी प्रकार के संशोधन अथवा फेरबदल की संभावना को भी नकारा था। साम्यवादी सांसद सोमनाथ चटर्जी ने 'माया' को बताया, "रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखते समय गृहमंत्री बूटा सिंह ने भी रिपोर्ट के अपूर्ण होने का किंचित मात्र संकेत नहीं दिया। बल्कि इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट के साथ सभी परिशिष्ट पेश किये जा रहे हैं। वह तो जब हम लोगों ने संसद के पुस्तकालय में रिपोर्ट की प्रति देखी, तो स्पष्ट हुआ कि इसके अधिकांश भाग गायब हैं।"

> ब्यौरे के अनुसार रिपोर्ट ४ भागों में है और हरेक भाग लगभग २००० पृष्ठों का है। किस भाग में क्या विषय है, इसका भी इसमें स्पष्ट उल्लेख है। नतीजतन ७०० से भी कम पृष्ठों और दो भागों में पेश रिपोर्ट पर हंगामा खड़ा होना लाजिमी था।

अपूर्णता का पता: सदन पटल पर रखी रिपोर्ट अपूर्ण है, इसकी जानकारी रिपोर्ट के पृष्ठ ७ का पैराग्राफ १.८.३ से मिली, जिसमें रिपोर्ट के अंशों का व्यापक ब्यौरा है। ब्यौरे के अनुसार रिपोर्ट ४ भागों में है और हरेक भाग लगभग २००० पृष्ठों का है। किस भाग में क्या विषय है, इसका भी इसमें स्पष्ट उल्लेख है। नतीजतन ७०० से भी कम पृष्ठों और दो भागों में पेश रिपोर्ट पर हंगामा खड़ा होना लाजिमी था। किंतु यह बात समझ में नहीं आती कि इतने गूढ़ निरीक्षण-परीक्षण के बाद रिपोर्ट में यह एक पैराग्राफ बना कैसे रह गया?

जब इसकी चर्चा एक जानकार सूत्र से चली, तो वह हंसकर बोला, "रिपोर्ट के प्रारंभ में ही इस पैरे का बना रहना दो ही संकेत देता है। प्रथम, रिपोर्ट का निरीक्षण-प्रकाशन बड़ी अफरातफरी में किया गया और यह अहम बात निगाहों से बच निकली। लेकिन बड़ी संभावना यह दिखायी देती है कि जो लोग इस समय सरकार के गले में फंदा डालने पर उतारू हैं, उन्होंने जानबूझकर ऐसे सांसतपूर्ण पैरे को रिपोर्ट के साथ जाने दिया है।"

जांच रिपोर्ट की प्रतियों की अनुपलब्धता भी विवाद का विषय है। समूचा गृह मंत्रालय दस दिनों तक पूर्ण सुरक्षा के माहौल में रिपोर्ट की प्रतियां तैयार करता रहा, लेकिन इसके बावजूद सांसदों को प्रतियां नहीं मिलीं। इसे सरकार की बदनीयती का परिचायक ही माना गया।

"बदनीयती ही नहीं, यह एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया"—ऐसा जनता दल के वरिष्ठ नेता एमएस गुरुपदस्वामी का मानना है, "एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका था, क्योंकि सरकार अपूर्ण रिपोर्ट पेश कर रही थी। इसके पीछे पूरी जानकारी को अधिक-से-अधिक समय तक टाले रखना भी था। साथ ही टुकड़ों-टुकड़ों में पेश कर उसके प्रभाव को कम-से-कम करना था।" दस दिन का इस्तेमाल सरकार ने प्रतियां बनाने की जगह, मूल प्रति में कटाई-छंटाई के लिए किया—ऐसा भी विपक्षी नेताओं का मानना है।

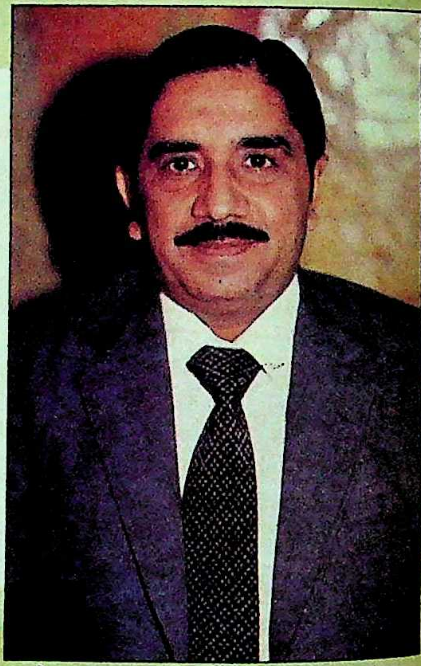

आरके धवन

अपूर्णता का विवाद: सरकार रिपोर्ट को अपूर्ण मानने को तैयार नहीं और वर्तमान हंगामा इसी मुद्दे को लेकर उठा है। पहले तो बाल की खाल यह दलील देकर निकाली जा रही है कि रिपोर्ट वस्तुत: है क्या? सरकार के अनुसार उसने अंतरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट पेश करके अपना दायित्व पूरा कर दिया है। यह दूसरी बात है कि पेश इन दोनों रिपोर्टों के कुल पृष्ठ ६५६ ही हैं, जबकि स्वयं

रिपोर्ट में दर्ज ब्यौरे के अनुसार कम-से-कम ८ हजार पृष्ठ होने चाहिए। कुछ सूत्र तो १२ हजार पृष्ठों की बात भी करते हैं।

सदन के भीतर-बाहर के उग्र विरोध के बाद यद्यपि गृहमंत्री बूटा सिंह ने अंततः स्वीकारा कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से रोक लिये गये हैं, किंतु हरकिशन लाल भगत के साथ एक साझा प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की रपटवाला हिस्सा संसद में पेश कर दिया गया है। केवल उसकी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज और परिशिष्ट रोके गये हैं। रिपोर्ट के रोके गये इन्हीं अंशों से संदेह-संशय और गहराया है। विपक्ष का मानना है कि रिपोर्ट के रोके गये इस ६० प्रतिशत अंश में षड्यंत्र संबंधी ऐसी सूचनाएं हैं, जिन्हें छिपाने को सरकार आतुर है। जाहिर है, वह किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय अथवा शक्ति को बचाने के लिए व्याकुल है। इसके ठीक विपरीत सरकार रिपोर्ट के उन अंशों को पटल पर न रखने के दो कारण बताती हैं: प्रथम, न्यायमूर्ति ठक्कर द्वारा निजी तौर पर सौंपी गयी रिपोर्ट के २२ दिन बाद भेजे गये ये दस्तावेज वस्तुतः रिपोर्ट का अंश ही नहीं हैं। दूसरे, जांच कार्यवाही से संबंधित ये हिस्से बेहद वर्गीकृत, नाजुक और गोपनीय दस्तावेज हैं। इनको जारी करना राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में नहीं होगा, क्योंकि इससे खुफिया एजेंसियों के कामकाज पर असर पड़ेगा।

राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित की बात सुनते ही विपक्षी नेता आगबबूला हो जाते हैं। मार्क्सवादी सांसद सैफुद्दीन चौधरी के अनुसार, "सरकार अब तक रिपोर्ट रोके रखने के लिए भी यही दलील देती रही थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद यह नतीजा निकलते देर नहीं लगी कि ये दोनों दलीलें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सरकार जिन दस्तावेजों को रिपोर्ट करार दे रही है, उनके अंश भी दबा लिये गये हैं। मसलन, अंतिम रिपोर्ट के पृष्ठ १३८ के 'अस्थिरता उत्पन्न करने में विदेशी दखलअंदाजी' के मुद्दे के हवाले में स्पष्टतया लिखा हुआ है, "आयोग द्वारा गहन अध्ययन और गंभीरतापूर्वक तैयार किया गया संपूर्ण मसौदा भाग एक (अ) अलग से दिया जा रहा है।" पटल पर रखी गयी रिपोर्ट में इस भाग एक (अ) का कहीं अता-पता नहीं। जाहिर है इसे सरकार ने दबा लिया है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार किसी विशेष एजेंसी का बचाव कर रही है।"

विदेशी षड्यंत्र?: उल्लेखनीय है कि सरकार रिपोर्ट पेश न करने के दौरान बराबर यही तर्क देती रही कि इससे बाहरी देशों व खासकर पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे। यद्यपि भाग एक (अ)—जिसमें विस्तृत हवाला है—उपलब्ध नहीं, किंतु इस मुद्दे पर रोशनी डालनेवाले अंतिम रिपोर्ट के पृष्ठ १३८ में न्यायमूर्ति ठक्कर ने स्पष्टतया कहा है, "प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की हत्या द्वारा भारत में अस्थिरता फैलाने के प्रयास में निश्चित रूप से विदेशी एजेंसी ने प्रमुख भूमिका निभायी है।" यही नहीं, न्यायमूर्ति ठक्कर ने इंदिरा गांधी के हत्यारों—बेअंत सिंह, सतवंत सिंह का किसी विदेशी शक्ति का मोहरा होने की संभावना को भी स्वीकारा है। सरकार ने इसके रहस्योद्घाटन की दिशा में कोई कारगर कदम उठाया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। किंतु यकायक व्यापक षड्यंत्र की बात सरकार अवश्य करने लग गयी है। एक आधिकारिक सूत्र ने 'माया' से कहा, "जब इस बात का खुलासा होगा कि यह षड्यंत्र कितना बड़ा था और इसमें कौन-कौन हस्तियां शामिल थी, तो समूचा देश हिल जायेगा। एक षड्यंत्रकारी तो अपनी गतिविधियां विदेश से संचालित कर रहा था।"

बूटा सिंह छाया: अशोक वाही

इस अंतिम रिपोर्ट में ही न्यायमूर्ति ठक्कर ने अंतरिम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देने का स्पष्ट सुझाव भी दिया है। लेकिन शायद रिपोर्ट को प्रकाश में लाना देश और जनता के बजाय सरकार के हित में नहीं था।

फोतेदार छाया: सुनील सक्सेना

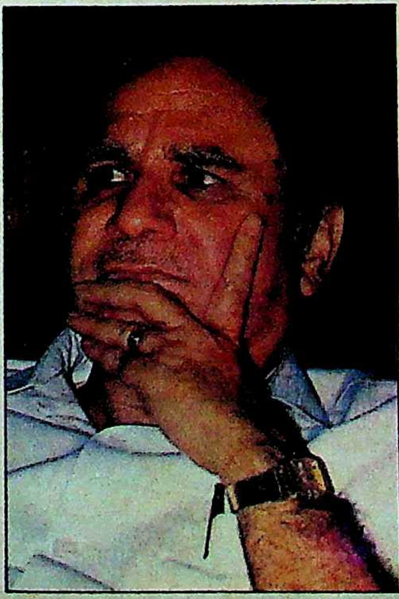

व्यापक षड्यत्र की बात सुनते ही जनता दल सांसद आरिफ मोहम्मद खां बोले, "इस व्यापक षड्यत्र की याद हमारे सदन के भीतर और बाहर मुहिम चलाने के बाद ही सरकार को आयी है। इसके पहले तो वह 'मित्रता बनाये रखने' के बहाने इस पर परदा डालने में अधिक जुटी थी। अगर कोई दूसरा देश इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल है, तो उसकी मित्रता बचाने की कोशिश राजीव गांधी करें तो शौक से करें। हमें उसकी मित्रता नही चाहिए।"

सरकार के हाल के अन्य रुख ने भी संदेहों को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट को इतने वर्षों तक गुप्त रखने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया (यहां तक कि ताबड़तोड़ ढंग से अधिनियम में संशोधन किया), उसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया है। न्यायमूर्ति ठक्कर के जिस सुझाव पर रिपोर्ट को गुप्त रखने की बात निरंतर दोहरायी गयी, वह सुझाव उन्होंने मात्र अंतिम रिपोर्ट के संबंध में दिया था। इस अंतिम रिपोर्ट में ही न्यायमूर्ति ठक्कर ने अंतरिम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देने का स्पष्ट सुझाव भी दिया है। लेकिन शायद रिपोर्ट को प्रकाश में लाना देश और जनता के बजाय सरकार के हित में नहीं था। यह बात उसके सार्वजनिक होने के बाद संसद, मीडिया और विधानसभाओं में उभरे व्यापक विवाद और बवंडर से स्पष्ट हो गयी है।

रिपोर्ट पेश करने की विवशता: विवाद और बवंडर की संभावना से कदाचित सरकार अनभिज्ञ नहीं थी और इसी कारण रिपोर्ट न पेश करने को कटिबद्ध थी। अतः रिपोर्ट प्रकाशन का निर्णय उसने बड़ी विवशता में ही लिया, इसमें दो राय नहीं। कारण एक नहीं, अनेक रहे:

◆ मंत्रियों—कांग्रेसियों द्वारा सार्वजनिक तौर पर चाहे कुछ भी कहा गया हो, किंतु मन में यह चोर अवश्य था कि 'इंडियन एक्सप्रेस' में जो छपा है, वह रिपोर्ट के ही उदघृत अंश हैं।

◆ चूंकि रिपोर्ट बाहर है, इसलिए इस क्रम के दोहराये जाने का भी पूर्ण अंदेशा था।

◆ बताया जाता है कि गुप्तचर विभाग द्वारा सरकार को यह रिपोर्ट भी दे दी गयी थी कि १७ से २७ मार्च के बीच के अवकाशकाल के दौरान रिपोर्ट के कुछ और विस्फोटक अंश भी प्रकाशित कर दिये जायेंगे। सरकार ने सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आग में

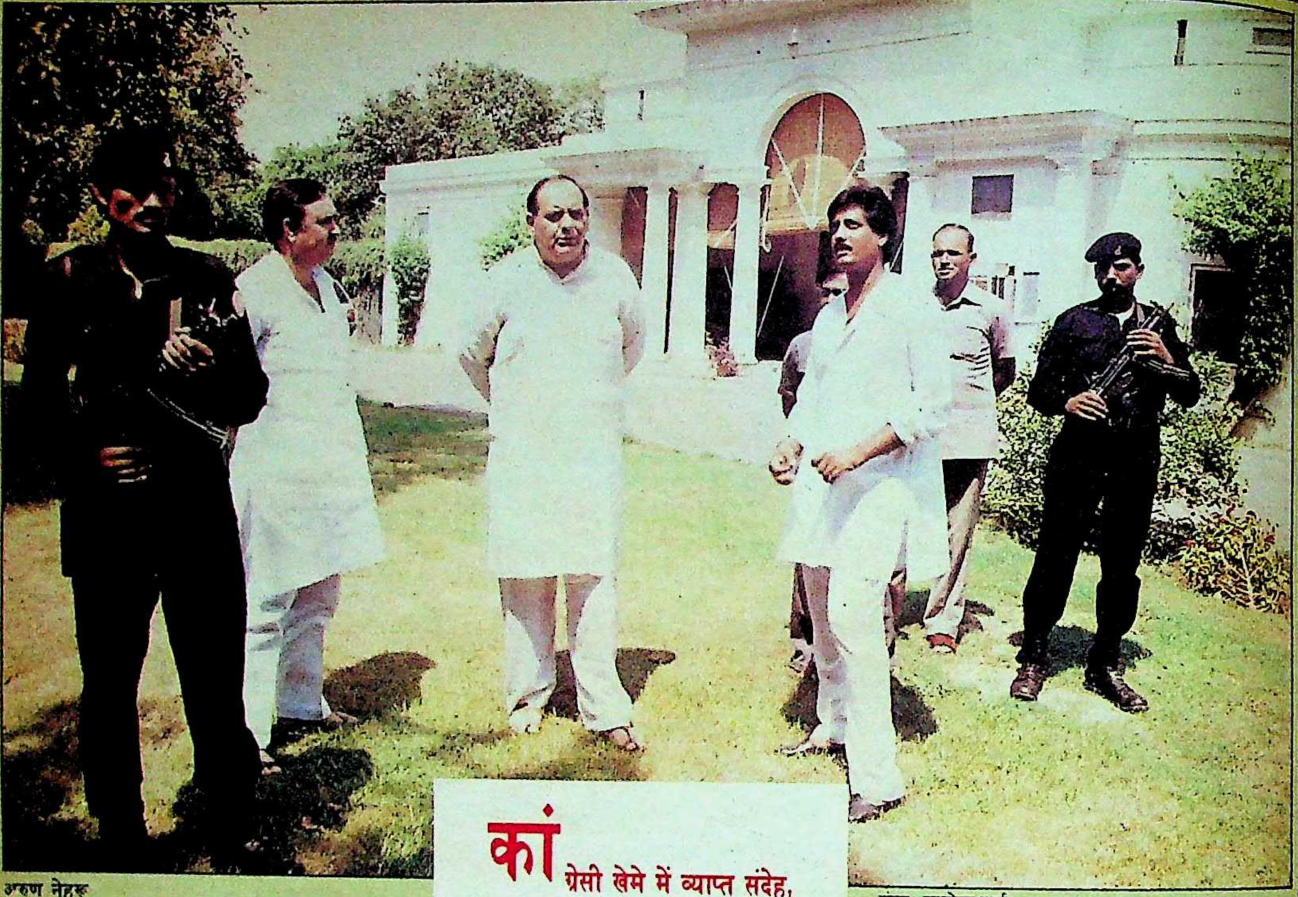

अरुण नेहरू

छाया: मनमोहन शर्मा

पानी डालने में ही खैर समझी।

◆ यह मुद्दा केंद्र तक ही सीमित नहीं रह गया था। राज्यों के स्तर पर भी यह उभरने और उग्र रूप धारण करने लगा था। इससे आरोप की उंगली सीधे-सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके परिवार की ओर उठने लगी थी। इस पर रोकथाम न लगाना आत्मघाती साबित होता। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि शक की सुई परिवार के दायरे से हटाने के लिए ही गत १७ मार्च को दूरदर्शन के समाचार के दौरान जब ठक्कर जांच रिपोर्ट को सदन में रखने के ऐलान की सूचना प्रसारित की गयी, तो साथ में श्रीमती गांधी के शव के निकट खड़े शोकग्रस्त अश्रुपूरित गांधी परिवार को दिखाया गया। उद्देश्य था सहानुभूति लहर पुनः जगाने-उभारने और भुनाने का।

◆ सर्वाधिक प्रभाव डालनेवाला मुद्दा १७ मार्च की सुबह संपूर्ण विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक का रहा, जिसमें एकजुट हो सरकार विरोधी मुहिम के अतिरिक्त सरकार को जनता की अदालत में ले जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत संपूर्ण विपक्ष द्वारा देशव्यापी जनसभाएं करने का कार्यक्रम तो बना ही, साथ ही २५ मार्च को 'भारत बंद' आयोजित करने और असहयोग आंदोलन के तहत 'जेल भरो' आंदोलन चलाने का आह्वान भी किया गया। चुनाव वर्ष में विपक्ष के राजनीतिक लाभ उठाने के मंशा से परिपूर्ण इस अभियान के परिणाम से सरकार अपरिचित नहीं थी। नतीजतन एकमात्र सुलभ रास्ता रिपोर्ट के प्रकाशन की हामी भरना था।

> कांग्रेसी खेमे में व्याप्त संदेह, संशय और हड़कंप भी कुछ कम चिंताजनक नहीं था। 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी रिपोर्ट के अंश से हर कांग्रेसी के मन में संदेह का जो बीजारोपण हुआ, उससे स्वयं एक कांग्रेसी सांसद के अनुसार 'पार्टीजनों का तन संसद के भीतर पार्टी के साथ अवश्य था, किंतु मन अधिकांश का नहीं था।'

◆ विपक्ष के अतिरिक्त कांग्रेसी खेमे में व्याप्त संदेह, संशय और हड़कंप भी कुछ कम चिंताजनक नहीं था। 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी रिपोर्ट के अंश से हर कांग्रेसी के मन में संदेह का जो बीजारोपण हुआ, उससे स्वयं एक कांग्रेसी सांसद के अनुसार 'पार्टीजनों का तन संसद के भीतर पार्टी के साथ अवश्य था, किंतु मन अधिकांश का नहीं था।' इस गंभीर मानसिक उथल-पुथल को मुखर होने का तब अवसर आ गया, जब ६३ विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। अगले ही दिन सत्ता पक्ष के सांसद राव वीरेंद्र सिंह और सीपीएन सिंह ने सदन में विद्रोह का झंडा उठाकर समस्त कांग्रेसियों में व्याप्त असंतोष, आक्रोश को मुखरित कर दिया। वरिष्ठ सांसद एजी कुलकर्णी रिपोर्ट के सदन पटल पर रखने की मांग पहले ही कर रहे थे। निलंबित कांग्रेस सांसद चिमनभाई मेहता भी यह मांग दोहराने में कोताही नहीं बरत रहे थे।

◆ सदन के बाहर तो विद्रोह और भी उग्र और व्यापक था। विपक्षी सदस्यों के 'अलोकतांत्रिक, अशालीन व्यवहार' की भर्त्सना और उनके निलंबन संबंधी बयान पर स्वीकृति की मोहर लगाने के लिए चलाये गये हस्ताक्षर अभियान के सिलसिले में संसद के केंद्रीय कक्ष में बैठे चंद छुटभैये नेताओं तक ने लगभग दुतकारते हुए

कहा, "तुम्हारे कहने से नहीं, प्रधानमंत्री कहेंगे तो दस्तखत करूंगा।" यही नहीं अंततः जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम से उक्त बयान जारी हुआ, उनके संबंध में भी यह अफवाह फैली कि उनमें से कइयों के हस्ताक्षर जाली थे।

◆ रिपोर्ट पेश करने के एक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारण राष्ट्रपति वेंकटरमण भी रहे। उल्लेखनीय है कि ठक्कर जांच आयोग की मांग को लेकर समूचा विपक्ष राष्ट्रपति के पास फरियाद के लिए पहुंचा था। इससे पूर्व जनता दल नेता अरुण नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति से ४० मिनट की लंबी भेंट की थी। इसके तुरंत बाद से सत्ता-गलियारों में अटकलें इस बात की लगायी जाने लगीं कि या तो नेहरू राष्ट्रपति को ठक्कर रिपोर्ट देने गये थे या देने की पेशकश कर आये थे। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से इसी रिपोर्ट को लेकर झंझट पहले ही हो चुका था। इसके पूर्व कि वर्तमान राष्ट्रपति से भी विवाद और मनमुटाव की नौबत आये, सरकार ने रिपोर्ट को संसद में पेश करने में ही खैर समझी।

◆ बढ़ते तूफान को शांत करने और क्षति को सीमित करने के अतिरिक्त राजेन्द्र कुमार धवन को आरोपों के चक्रव्यूह से मुक्त कराना भी एक फौरी जरूरत बन गयी थी। नतीजतन १७ मार्च को ही राजनीतिक मामलों की कैबिनट समिति की आवश्यक बैठक बुलाकर रिपोर्ट पेश करने के विषय में विचार-विमर्श कर उसे संसद में पेश करने का फैसला ले लिया गया। उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ऐलान किया कि होली के अवकाश के बाद २७ मार्च को जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रख दी जायेगी।

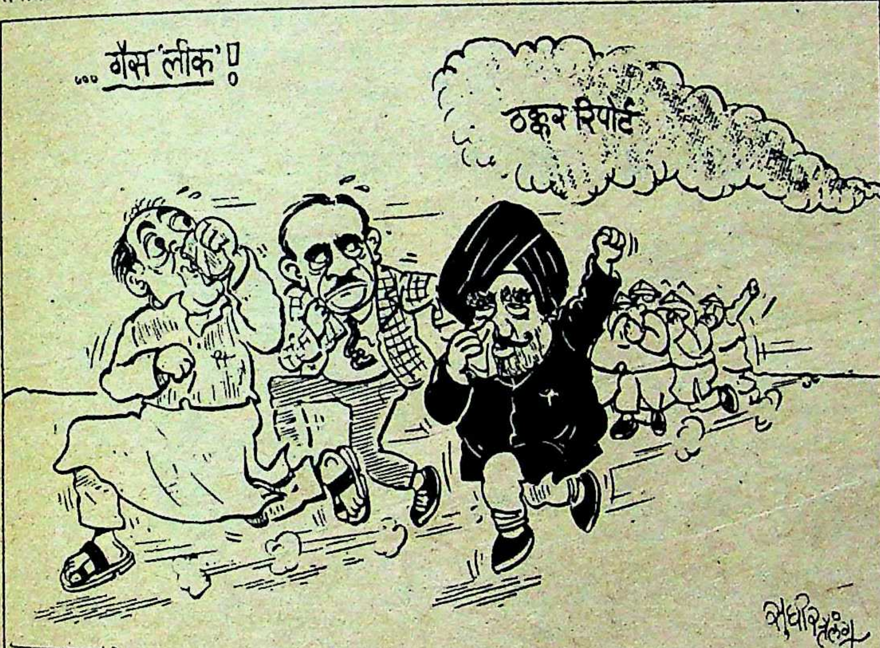

'नवभारत टाइम्स' से साभार

धवन पर शक : जहां तक श्री धवन का प्रश्न है, न्यायमूर्ति ठक्कर ने शक की सुई उनकी ओर टिकाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। समूची जांच प्रक्रिया में धवन ठक्कर के दिलोदिमाग में किस कदर छाये हुए थे, वह इसी बात से स्पष्ट है कि ३१३ पृष्ठ की अंतिम रिपोर्ट में २१४ पृष्ठ केवल 'किस्साये धवन' से परिपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति ठक्कर के अनुसार, "बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के अपराध को सुगम बनाने में श्रीमती गांधी के विशेष सहायक श्री धवन की भूमिका रही है। धवन के अलावा हत्या में किसी अन्य व्यक्ति का शामिल होना भी असंभव नहीं है। जांच की रोशनी धवन पर केंद्रित करके ही इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है।"

श्रीमती गांधी की छाया के समान लगातार २० वर्षों तक साथ रहने वाले श्री धवन को लेकर आयोग ही नहीं, समूचे देशवासियों के मन में यह शंका बनी हुई है कि उनकी ऐन मौजूदगी में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की बर्बर हत्या निर्विघ्न कैसे कर दी गयी? विशेषकर इसलिए कि जिस गोलीबारी में श्रीमती गांधी का शरीर छलनी हो गया था, उसमें धवन को खरोंच भी न आयी थी। ठक्कर आयोग के शक की वजह पांच मुख्य बातें रही हैं:

- पीटर उस्तीनोव की टेलीविजन टीम से प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के साक्षात्कार के पूर्व निश्चित समय को रहस्यमय ढंग से बदला जाना।
- इंदिरा गांधी के इर्द-गिर्द सिख सुरक्षाकर्मियों की वापस तैनाती श्रीमती गांधी के नाम पर धवन के कहने पर हुई।
- आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रातः ११ बजकर ४२ मिनट पर धवन ने वायरलेस संदेश से हत्यारों—बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के बारे में

साक्षात्कार/आरिफ मोहम्मद खां

अथारिटी अब धवन हैं, न कि राजीव गांधी

माया : धवन को वापस बुलाये जाने का क्या महत्व है?

आरिफ मोहम्मद खां : *धवन को वापस बुलाने पर राजीव गांधी की जिस तरह तारीफ हुई है, उससे तो ऐसा लगता है कि चिमन भाई मेहता की अपील मानकर राजीव गांधी ने पार्टी-नेतृत्व के लिए विकल्प ढूंढ़ लिया है। मालूम होता है कि राजीव को अपना विकल्प मिल गया। शायद इसीलिए अब लोगों की राय है कि 'अथारिटी' अब धवन हैं, न कि राजीव गांधी।*

माया : आरोप है कि अरुण नेहरू ने ठक्कर रिपोर्ट को 'लीक' किया है। कल्पनाथ राय तथा केके तिवारी जैसे मंत्रियों ने साक्षात्कारों में ऐसा ही कहा है?

खां : *अगर वे यह निश्चित रूप से जानते हैं कि रिपोर्ट अरुण नेहरू ने 'लीक' की है, तो वे सफाई दें कि उनकी सरकार ने अब तक नेहरू के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और क्यों तिवारी ऐसी सरकार की सेवा कर रहे हैं? अगर वे किसी जांच की मांग करें, तो मैं उनसे सहमत हूं। फिर भी अगर जांच न की जाये, तो उनका नैतिक दायित्व क्या बनता है? वे ऐसी सरकार में कार्य कर रहे हैं, जो उन्हें कोई महत्व नहीं देती।*

माया : आप सब (विपक्ष) यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को छिपा रही है जिनकी मिलीभगत और लापरवाही से श्रीमती गांधी की हत्या हुई। आपके इस संदेह का आधार क्या है?

खां : *पिछले कुछ दिनों के दौरान मुझे पता चला कि संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद एपी शर्मा तथा सीपीएन सिंह ने न्यायिक जांच का आदेश दिया था। शर्मा तब नागरिक उड्डयन मंत्री थे और सिंह रक्षा मंत्री। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री के किसी नजदीकी प्रिय आदमी ने इस जांच को तोड़-मरोड़ दिया। अगर यह जांच न बिगाड़ी गयी होती, तो शायद बाद में राष्ट्रीय क्षति टाली जा सकती थी। हमारा सवाल है कि ठक्कर रिपोर्ट क्यों छिपायी गयी थी? किसके फायदे के लिए छिपायी गयी थी? और ज्यादातर दोषी ठहराये गये लोग अच्छी स्थिति में क्यों बने हुए हैं?* ■

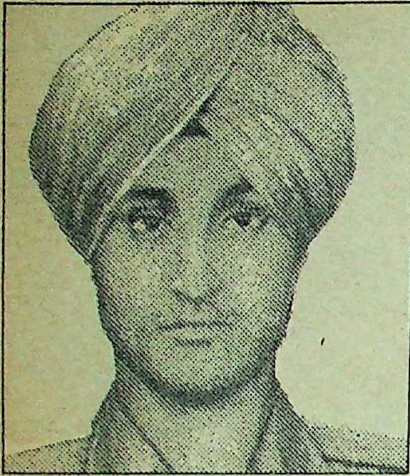

फांसी : सतवंत सिह

पूछा कि उनका क्या हुआ ?

० बेअंत सिह ने धवन पर गोली नही चलाने की सावधानी बरतने के लिए सतवंत सिह से क्यों कहा ?

० धवन 'लाई डिटेक्टर' (झूठ पकड़ने की मशीन) की जांच के लिए तैयार नहीं हुए। (देखिए बाक्स-धवन के बचाव में)।

विडंबना है कि कांग्रेस और सरकार को बचाने के लिए धवन की वापसी हुई थी, लेकिन आज उन्ही की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी और सरकार को कमर कसनी पड़ी है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को जो गंभीर संदेह के घेरे में आबद्ध हो, ऐसा महत्वपूर्ण पद क्यों दिया गया है ? क्या ठक्कर के संदेह निराधार थे ? धवन को बरी करने के आधार क्या थे ? इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धवन के खिलाफ रंगे २१४ पृष्ठों को तो सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है, किंतु आनंद राम की अध्यक्षतावाली जिस विशेष जांच समिति (एसआईटी) द्वारा धवन को निर्दोष करार दिये जाने की दुहाई दी जा रही है, उसकी रिपोर्ट को गुप्त रखा गया है। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के अनुसार इंडियन एक्सप्रेस के भंडाफोड़ से कहीं अधिक घातक सरकार की 'एसआईटी' रिपोर्ट दबाने की हरकत सिद्ध हुई है, जिसने धवन और सरकार दोनों के विरुद्ध संदेहों को और गहरा किया है।

सरकार के अनुसार धवन की नियुक्ति से पूर्व एसआईटी रिपोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त प्रमाणपत्र दिया था। 'माया' को विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि 'एसआईटी' रिपोर्ट को सार्वजनिक न बनाने के लिए सरकार के सामने फिलहाल दो विवशताएं हैं। पहली यह कि यह एक सुगठित रिपोर्ट के रूप में न होकर छुटपुट नोट्स, टिप्पणियों की शक्ल में है। दूसरे, इसको जारी करने की तारीख को लेकर गृह मंत्रालय में विवाद है, जिसके चलते संबंधित अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे हैं।

जहां तक विपक्ष का सवाल है, वह तो 'एसआईटी' के अधिकार क्षेत्र पर ही प्रश्नचिह्न लगा रहा है। ज्ञात रहे कि 'एसआईटी' वही संगठन है, जिसके सुझावों, साक्ष्यों और जांच पर ही ठक्कर आयोग अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है। अतः आयोग की सिफारिशों पर इसी संगठन को जांच-परख करने और मुहर लगाने की जिम्मेदारी सौंपना अपने आप में एक अजूबा है। आरिफ मोहम्मद खा ने 'माया' से बातचीत में कहा, "पुलिस जांच और रिपोर्टों को न्यायालय और न्यायाधीशों द्वारा रद्द किये जाने की अनेक मिसालें हैं। किंतु पुलिस जांच से सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की रिपोर्ट रद्द की जाये, ऐसा अंधेर राजीव राज में ही संभव है।"

धवन की बेगुनाही : धवन की निर्दोषता का उल्लेख करते हुए कांग्रेस सांसद पीएन मुकुल बोले, "कोई भी अपराध किसी हितलाभ के तहत किया जाता है। श्रीमती गांधी की हत्या से धवन को भला क्या हासिल होने वाला था ? श्रीमती गांधी तो धवन का शक्तिस्रोत थीं।" आधिकारिक सूत्र भी न्यायमूर्ति ठक्कर के शक के प्रमुख कारणों की एक-एक कर धज्जियां उड़ाने में कोताही नहीं करते।

उनके अनुसार श्रीमती गांधी व आयरिश टीवी टीम से साक्षात्कार का तय समय बदला जाना इसलिए महत्वपूर्ण नही माना जा सकता क्योंकि हत्यारे बेअंत सिह व सतवंत सिह की ड्यूटी उस दिन प्रातः ७ बजे से दोपहर २ बजे तक थी। आधे घंटे का हेरफेर उनकी कार्यसिद्धि में कतई बाधक नहीं होता। रपट में डीसीपी जीआर गुप्ता का हवाला देकर कहा गया है कि श्रीमती गांधी की सुरक्षा में सिख पुलिसकर्मियों की वापसी धवन के निर्देश पर हुई। प्रश्न है कि आयोग ने उसी जीआर गुप्ता की

साक्षात्कार/केके तिवारी

अरुण नेहरू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए

माया : *आपके विचार में किस ने इस रिपोर्ट का हिस्सा 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपवाया ?*

तिवारी : अरुण नेहरू को छोड़कर और कोई हो ही नहीं सकता।

माया : *तो आपने या सरकार ने इसके बारे में नेहरू से क्यों नहीं जवाब तलब किया ?*

तिवारी : मैं तो यह चाहूंगा कि इस बारे में अलग से जांच बिठा दी जाये कि अरुण नेहरू—जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे—की इंदिरा गांधी की हत्या के समय क्या भूमिका थी और जब दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, तो उन्होंने क्या हथकंडे अख्तियार किये ?

माया : *फिर राजीव गांधी ने ढाई से तीन साल तक उन्हें अपना निकटतम सहयोगी और विश्वासपात्र क्यों बनाया ? इससे तो राजीव गांधी की राजनीतिक समझ पर शंका होती है ?*

तिवारी : दुनिया जानती है कि इंदिराजी की हत्या के बाद राजीवजी की मानसिक दशा क्या थी। फिर अरुण नेहरू जैसे लोग अपने बारे में विश्वास पैदा कराने में माहिर होते हैं।

माया : *आपने कहा कि अरुण नेहरू प्रधानमंत्री होने के सपने देख रहे थे... ?*

तिवारी : मेरे खयाल से संजय गांधी के मरने के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अरुण नेहरू का नाम चर्चित हुआ, उससे उनको यह भ्रम होने लगा कि वे इंदिराजी के असली उत्तराधिकारी हैं। मगर उनके सब मंसूबे तब ढह गये जब पार्टी ने यह निश्चय किया कि राजीव गांधी को राजनीति में लाया जाये। मैं फिर कहूंगा कि अरुण नेहरू की इंदिरा गांधी की हत्या के समय क्या भूमिका थी, इसकी जांच होनी चाहिए।

माया : *मगर इस वक्त धवन के बारे में रिपोर्ट छपवाने से अरुण नेहरू को क्या फायदा हो सकता था ? इससे ज्यादा संभावना तो धवन की पुनः नियुक्ति से कुछ कांग्रेसी नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी की थी।*

तिवारी : नेहरू हमेशा से धवन के विरुद्ध रहे हैं। और भी कुछ लोग जो नेहरू के नजदीक थे, धवन के खिलाफ हैं।

माया : *अगर ऐसे लोग सरकार में भी हैं, तो उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते ?*

तिवारी : मैं उन लोगों के नाम अभी नहीं लूंगा।

बात को आधार कैसे मान लिया, जिसे स्वयं उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में गैरजिम्मेदार ठहराया है? आयुर्विज्ञान सस्थान से हत्यारों के बारे में धवन की पूछताछ के संदर्भ में सवाल उठता है कि ऐसी बात होती, तो धवन वायरलेस का उपयोग कतई न करते। उनकी पूछताछ का कारण स्वाभाविक कौतूहल भी हो सकता था। धवन पर गोली नहीं चलाने की सतवंत को बेअंत द्वारा दी गयी कथित हिदायत के संबंध में कहा जाता है कि आनंद राम जांच टीम के सामने ही सतवंत सिह ने पहले बयान दिया था कि किसी निर्दोष को गोली नहीं लगनी चाहिए। लाई डिटेक्टर के संबंध में भी यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि धवन ने इनकार नहीं किया था, आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था।

जहां तक धवन की बेगुनाही का प्रश्न है, अनेक विपक्षी नेता भी इसे स्वीकारते हैं। किंतु जैसाकि सैफुद्दीन चौधरी का दावा है, "आरोप गंभीर भी हैं और सार्वजनिक भी। इसलिए उसकी गहन गंभीर और सार्वजनिक जांच भी नितांत आवश्यक है। विशेषकर इसलिए कि ठक्कर जांच आयोग की रिपोर्ट का पूरा जोर धवन पर शक की सुई टिकाने का रहा और ऐसा लगता है कि एसआईटी का पूरा जोर उन्हें निर्दोष साबित करने का।" हुआ भी ऐसा ही है। स्वयं धवन ने रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद स्वीकार किया है कि वे एक राजनीतिक साजिश के शिकार हुए थे। जानकार सूत्रों के अनुसार धवन पहले तो राजघरानों जैसे षड्यंत्र के शिकार बन सत्ता गलियारे से बाहर किये गये, तत्पश्चात २० वर्षों के जानकार व्यक्ति का मुंह सिल देने के लिए ठक्कर आयोग की जांच में उन्हे इस बुरी तरह फंसा दिया गया कि जांच और उसकी रिपोर्ट की नंगी तलवार उनके सर पर लटकती रहे।

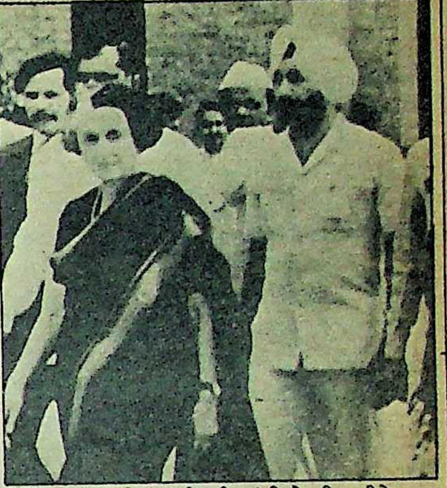

विश्वासघात: बेअंत श्रीमती गांधी के ठीक पीछे

धवन की रणनीति: उक्त सूत्र के अनुसार राजनीतिक हथकंडों में माहिर धवन बहुत जल्दी ही अपने खिलाफ रची गयी इस साजिश को समझ गये। नतीजतन अपने हर बयान और स्पष्टीकरण में वे राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लपेटने लगे। मसलन, जब आयोग ने धवन की डायरी के एक पृष्ठ पर अंकित 'विदेशी धन—सतवंत सिह' के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, तो उन्होंने लिख भेजा कि "जहां तक मुझे याद है यह, मैंने तब लिखा था, जब श्री राजीव गांधी ने अपने निवास स्थान पर मुझसे बातचीत करते हुए श्रीमती गांधी की हत्या के बाद विदेशी धन और सतवंत सिंह के बारे में उठ रही अफवाहों का जिक्र किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह मामला बहुत गंभीर है। इसकी छानबीन होनी चाहिए। जहां तक मुझे याद है, इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने के बारे में याद दिलाने को कहा था।"

धवन की रणनीति स्पष्ट थी। उनके द्वारा अन्य लोगों का नाम लिये जाने से आयोग के लिए उनका भी बयान लेना अनिवार्य हो जाता। जानकार सूत्रों के अनुसार लाई डिटेक्टर जांच के संबंध में भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने अप्रत्यक्ष संकेत यह दे दिया कि लाई डिटेक्टर के अंतर्गत उनके मुंह से क्या-क्या निकल जायेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उनकी यह रक्षानीति सफल साबित हुई। अंततः आयोग का कसता फंदा भी ढीला पड़ा और लाई डिटेक्टर से भी उन्हें बरी रहना पड़ा।

धवन की निर्दोषता के बारे में उच्च नेतृत्व भलीभांति परिचित था। अतः जब धवन की वापसी पार्टी और सरकार के लिए अनिवार्य हो गयी, तो 'एसआईटी' के जरिए उनके दोषमुक्त होने का प्रमाणपत्र हासिल करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार धवन की बहाली हो गयी। किंतु विडंबना यह

श्रीमती गांधी के अंतिम क्षण

जिस घटनाक्रम की परिणति ३१ अक्तूबर, १९८४ को इंदिरा गांधी की हत्या में हुई, उसे आरके धवन ने ठक्कर आयोग के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया है:

"हमेशा की तरह, मैं सवेरे करीब ८.१५ बजे पीएम हाउस पहुंचा। करीब ८.३० बजे, जब वे बाल कटवा चुकीं, (स्व०) प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया और उसी दिन शाम को राजकुमारी ऐन के सम्मान में आयोजित होनेवाले भोज के लिए अतिथियों की सूची पर बातचीत की। इसके बाद करीब ९.बजे मेरे कमरे में आकर उन्होंने उस फिल्मांकन की तैयारी की जानकारी ली, जिसकी व्यवस्था १, अकबर रोड पर की जा रही थी।

"मुझे शारदा प्रसाद (श्रीमती गांधी के सूचना सलाहकार) ने बताया था कि १, अकबर रोड पर गार्डन की सफाई की जा रही है, इसलिए वे (श्रीमती गांधी) ५-१० मिनट बाद वहां पहुंच सकती हैं। यह सूचना उन्हें दे दी गयी और वे अपने कमरे में चली गयीं। करीब १० मिनट बाद मैं भोजन कक्ष के बाहर गया। करीब ९.१० बजे वे भी भोजन कक्ष से बाहर निकलीं और हम १, अकबर रोड की तरफ चल पड़े। नाथू राम और एक सुरक्षा सहायक नारायण सिंह भी हमारे साथ थे। रास्ते में उनसे एक बेयरा मिला। वह अकबर रोड से हाथ में प्याले और तश्तरियां लिए लौट रहा था। उसने उन्हें बताया कि फिल्मनिर्माता ट्रे में रखा एक पूरा टी-सेट मांग रहे हैं।

"इसके बाद फिर वे पैदल आगे बढ़ीं। जब हम अकबर रोड गेट के पास पहुंचे, तब अचानक हमें गोली छूटने की आवाज सुनायी पड़ी और जब मैंने सिर ऊपर उठाया, तो बेअंत सिंह को (जिसका नाम मैंने इस घटना के बाद ही जाना) अपने रिवाल्वर से उन पर फायर करते हुए देखा।

"उसने जैसे ही फायरिंग खतम की, सतवंत सिंह (यह नाम भी मैंने घटना के बाद ही जाना) कुछ कदम आगे बढ़ा और अपने (स्वचालित) हथियार से गोलियां बरसाने लगा। मैंने यह भी देखा कि बेअंत सिंह ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिये। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को देखता, इसके पहले वे जमीन पर गिर पड़ी थीं।

"मैं डाक्टर बुलाने के लिए चिल्लाया। तब तक श्रीमती सोनिया गांधी घटनास्थल पर पहुंच गयीं। एक डाक्टर भी पहुंचा (जिसका नाम मैं नहीं जानता)। मैंने एंबुलेंस मांगी। इस बीच फोतेदार भी वहां पहुच गये। एंबुलेंस नहीं आयी, तब मैंने कहा कि जो भी गाड़ी मिले, वह तुरंत लायी जाये। तब तक शारदा प्रसाद और सुरक्षा-अधिकारी श्री भट्ट भी वहां पहुंच गये।

"सुरक्षा अधिकारी एक एंबेसडर कार ले आये। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। कार में मैं, श्रीमती सोनिया, श्री भट्ट, फोतेदार और डाक्टर थे। भट्ट ने कहा कि हमें आयुर्विज्ञान संस्थान चलना चाहिए, क्योंकि वहां आवश्यक उपचार की सारी सुविधाएं हैं। संभवतः किसी ने भी अस्पताल को (इस घटना की) सूचना नहीं दी थी और कार में बैठे किसी भी आदमी को यह जानकारी नहीं थी कि कहां यह सूचना दी जाये। जब हम आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे, तो उसके प्राइवेट वार्ड का फाटक बंद था। मैंने ड्राइवर से कार पीछे से ले चलने और 'कैजुअलिटी' में सूचना देने को कहा।

"जब हम 'कैजुअलिटी' में पहुंचे, तब हमने एक स्ट्रैचर मांगा। वह तत्काल लाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी 'कैजुअलिटी' के अंदर ले जायी गयीं और डाक्टर उनके उपचार में लग गये। ५ मिनट बाद आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक सहित वरिष्ठ डाक्टर वहां आ गये और श्रीमती गांधी को देखने लगे।"

किंतु श्रीमती गांधी थीं कहां? वह तो उनका पार्थिव शरीर था—गोलियों से छलनी हुआ शरीर!

—वशिष्ठ

है कि जिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट की नंगी तलवार धवन के सर पर लटकायी गयी थी, वही अब सरकार के ऊपर टंग गयी है।

जनता दल सांसद जयपाल रेड्डी के अनुसार सरकार की स्थिति ऐसी सांसतपूर्ण हो गयी है कि उसके लिए ठक्कर और धवन का एक साथ रक्षाकवच बनना अनिवार्य हो गया है और यह असंभव-सा कार्य बन गया है। कारण, वह अगर ठक्कर का एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में समर्थन करती है, तो उसे धवन को दोषी मानना चाहिए, जिनके विरुद्ध न्यायमूर्ति ठक्कर ने इतने गंभीर आरोप लगाये हैं। ऐसी हालत में धवन की बहाली का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसके विपरीत यदि वह धवन को निर्दोष मानती है, तो इसका अर्थ है, ठक्कर एक अक्षम न्यायाधीश हैं। ऐसी सूरत में न्यायमूर्ति को पहले फेयरफैक्स का अध्यक्ष नियुक्त करना और अब सेवामुक्ति के बाद ५ वर्ष के लिए विधि आयोग का अध्यक्ष बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। किया सरकार ने अंततः यही। धवन की बहाली भी की और ठक्कर को पुरस्कृत भी। जयपाल रेड्डी ने आगे जोड़ा, "ऐसी सरकार को क्या कहें जो दोनों (ठक्कर-धवन) को पुरस्कृत करती है। क्या यह इस शक को बढ़ावा नहीं देती कि यह सरकार श्रीमती गांधी की हत्या के संबंध में किसी विस्फोटक तथ्य को छिपाना चाहती है?" लेकिन कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा भी है जो यह प्रचार कर रहा है कि हो न हो, रिपोर्ट को लीक स्वयं ठक्कर ने ही किया है, क्योंकि उन्हें धवन के उभरने से खतरा था। (देखिए बाक्स)।

रिपोर्ट में मात्र धवन को ही नहीं, बल्कि २१ अन्य अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। रिपोर्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कई अधिकारियों की गलतियों और लापरवाहियों की ओर संकेत करते हुए उन्हें दोषी ठहराती है। किंतु सेवा में लापरवाही बरतने के लिए अधिकांश को दंडित करने की जगह पुरस्कृत किया जाना संदेह को और पुख्ता बनाता है (देखें बाक्स)। आयोग की रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि यदि हरेक अपनी ड्यूटी में खरा उतरता, तो श्रीमती गांधी की हत्या न हुई होती। इस दुर्घटना ने उस व्यवस्था का भी पर्दाफाश किया है जो श्रीमती गांधी चला रही थीं और जिसमें समस्त सत्ता एक व्यक्ति—श्री धवन—के हाथ में इस हद तक केंद्रित हो गयी थी कि कोई अन्य व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा था।

इस रिपोर्ट के संदर्भ में दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जिस रिपोर्ट में समस्त सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आ जाने के दुष्परिणामों को दर्शाया गया है, उस रिपोर्ट के प्रस्तुत हो जाने के बाद भी सत्ता पर एक व्यक्ति के काबिज रहने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा गया। ठक्कर द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के समय वित्तमंत्री और सरकार में नंबर दो रहने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वीकारा है कि उन्होंने रिपोर्ट कभी देखी नहीं। इससे भी आश्चर्यजनक तत्कालीन कानून मंत्री अशोक सेन की रिपोर्ट को न देखने की स्वीकारोक्ति है, जिसको गुप्त रखने का विधेयक उन्होंने स्वयं संसद में प्रस्तुत किया था।

विपक्ष पर आरोप : केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कमल कांत तिवारी के अनुसार जो विपक्षी नेता आज यकायक श्रीमती गांधी के हिमायती हो गये हैं, वे चार वर्ष तक चुप क्यों रहे? वे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो आज बढ़-चढ़कर बातें कर रहे हैं, उस समय क्यों चुप रहे, जब वे वित्तमंत्री और राजनीतिक मामलों की कैबिनट समिति के सदस्य थे। जिस न्यायमूर्ति ठक्कर की जांच रिपोर्ट की दुहाई आज समूचा विपक्ष दे रहा है, उसी न्यायमूर्ति ठक्कर ने

साक्षात्कार/**विश्वनाथ प्रताप सिंह**

राजीव गांधी को इस्तीफा देना चाहिए

माया: कुछ केंद्रीय मंत्रियों, मसलन कमल कांत तिवारी और कल्पनाथ राय का आरोप है कि ठक्कर आयोग जांच रिपोर्ट के अंश आपके दायें हाथ और सहयोगी अरुण नेहरू ने आपकी स्वीकृति से 'लीक' किये हैं?

सिंह: इस तरह के बेबुनियाद आरोप अन्य लोगों पर लगाकर सरकार अपनी गैरजिम्मेदारी और अक्षमता को ढांकने का प्रयास कर रही है। सरकार ने उक्त रिपोर्ट को गुप्त रखने का अनुरोध कर संसद से विशेष अधिकार प्राप्त किया था। यह जिम्मेदारी सरकार की थी कि वह सदन के विश्वास को बनाये रखने के अपने कर्तव्य को निभाये। लेकिन सरकार ठक्कर आयोग जांच रिपोर्ट को गुप्त नही रख पाई।

बजट पेश होने से पूर्व उसकी गोपनीयता की जिम्मेदारी वित्तमंत्री की होती है। यदि वह किसी क्लर्क या चपरासी द्वारा भी 'लीक' कर दी जाये तो इस्तीफा वित्तमंत्री को देना पड़ता है। इसी प्रकार ठक्कर जांच रिपोर्ट के 'लीक' हो जाने से प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी सरकार को क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए?

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देश क्या विश्वास करे कि यह सरकार कोई

महत्वपूर्ण बात गुप्त रख सकेगी? मेरी समझ में राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा इस सरकार से है। मेरी जानकारी अथवा स्वीकृति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने तो पहली बार रिपोर्ट के उद्धृत अंश 'इंडियन एक्सप्रेस' में देखे। मैंने सदन में भी कहा है कि रिपोर्ट न तो कैबिनेट में रखी गयी और न ही कैबिनेट के राजनीतिक मामलों की समिति के सम्मुख। प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि जांच रिपोर्ट के प्रकाशन से इंदिरा गांधी हत्याकांड के मुकदमे पर विपरीत असर पड़ेगा, सबकी सहमति हासिल कर ली थी।

माया: ***रिपोर्ट को गोपनीय रखने के बारे में आपकी चुप्पी का क्या कारण रहा? क्या आप सही मौके की तलाश में थे?***

सिंह: जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वयं यह कहें कि इससे श्रीमती गांधी की हत्या के मुकदमे पर आंच आयेगी, तो कौन ऐसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर हठ कर सकता था? जब तक मुकदमा समाप्त न होता, हम क्या कर सकते थे?

यही नहीं जब मुकदमा खत्म हो गया, फांसी भी हो गयी और रिपोर्ट के अंश प्रकाशित भी हो गये, तब भी, जब विपक्ष ने उसे सदन के पटल पर रखने की मांग की तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार देश की सुरक्षा और जनहित की दुहाई देते हुए इसे गुप्त रखने के मुद्दे पर अड़ी रही। यह तो जनमत और विपक्ष की बढ़ती शक्ति देख प्रधानमंत्री ने चटपट घुटने टेक दिये। उस दिन देश की सुरक्षा और जनहित का क्या हुआ? जाहिर है, यह सब मात्र एक बहाना था।

मेरा तो मानना है कि सरकार के खिलाफ सबसे बड़े गवाह स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। सदन और जनता को गलतबयानी से गुमराह करनेवाले वे और उनकी सरकार ही रही। जाहिर है, जिन पदों पर ये लोग हैं, उनके वे योग्य नहीं।

—रंजना कक्कड़

गुनहगार सिर्फ धवन नहीं

राजेंद्र कुमार धवन ने कहा है कि ठक्कर आयोग की रपट का नाम बदल कर 'धवन को फांसी कैसे दी जाये' रख देना चाहिए। पर ठक्कर आयोग ने सिर्फ धवन को ही नहीं, बल्कि २१ अन्य अधिकारियों को भी लताड़ा है। आयोग का मानना है कि यदि ये लोग अपना कार्य ठीक प्रकार करते, तो श्रीमती गांधी की हत्या होने से रोकी जा सकती थी। न्यायमूर्ति ठक्कर के अनुसार, यदि सुरक्षा कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाते, तो जो नहीं होना चाहिए था, वह नहीं होता। ठक्कर आयोग द्वारा दोषी पाये गये २१ अधिकारियों में से ७ अभी तक बर्खास्त हैं। पर अन्य लोगों की पदोन्नति कर दी गयी है।

एमएमके वली: एमएमके वली तत्कालीन गृह सचिव, जिनके बयान को ही आयोग ने मानने से इनकार कर दिया था, बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल बना दिये गये। खुफिया ब्यूरो के निदेशक आरके कपूर ने आयोग के समक्ष अपने बयान में कहा था कि वली को सिख सुरक्षा कर्मचारियों की दोबारा तैनाती तथा उसके संभावित परिणाम की सूचना दे दी गयी थी। पर वली ने कोई कार्यवाही नहीं की। आयोग को दिये गये अपने बयान में वली ने कहा कि उन्हे ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी थी।

आरएन काव: आरएन काव कैबिनेट सचिवालय में वरिष्ठ सलाहकार (सुरक्षा) थे। साधारणतया महाजासूस कहे जानेवाले काव को भी आयोग ने अपना कार्य न करने के लिए लताड़ा था। लेकिन बाद में काव को सरकार ने विदेश मंत्रालय की नीति निर्माण समिति का सदस्य बना दिया। काव को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी परिवार के एक सदस्य के रूप में इज्जत देती थीं। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को सिख सुरक्षा कर्मचारियों से खतरे के प्रति आगाह नहीं किया।

सुभाष चंद्र टंडन: तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एससी टंडन की पदोन्नति कर राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम का अध्यक्ष और बाद में सेवा-निवृत्त होने के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया। ठक्कर आयोग ने टंडन को सिख कर्मचारियों पर निगाह न रखने के लिए बुरी तरह लताड़ा था।

एमएमके वली

आरएन काव

एस राममूर्ति: खुफिया आयोग के संयुक्त निदेशक एस राममूर्ति को सीआईडी पुलिस का आयुक्त बना दिया गया। राममूर्ति ने ही पूर्व सूचना सुरक्षा अधिकारियों को भेजी थी कि प्रधानमंत्री के जीवन को सिख सुरक्षा कर्मचारियों से खतरा है। लेकिन वे सूचना देकर ही संतुष्ट हो गये थे तथा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की।

आरके ओहरी: तत्कालीन सीआईडी पुलिस अतिरिक्त आयुक्त आरके ओहरी पर आयोग ने सिख सुरक्षा कर्मचारियों पर नजर न रखने का आरोप लगाया था। उन्हें बाद में पुलिस आईजी बना दिया गया।

एस रामकृष्णन: पुलिस विशेष शाखा के उपायुक्त एस रामकृष्णन अब भी सीआईडी पुलिस के अतिरिक्तायुक्त का पद संभाले हुए हैं। रामकृष्णन के खिलाफ आरोप था कि सिख सुरक्षा कर्मचारियों से संबंधित फाइल पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

डीके भट्ट: प्रधानमंत्री के तत्कालीन निजी सुरक्षा अधिकारी डीके भट्ट जो हत्या के समय प्रधानमंत्री के पास नहीं थे, अभी भी दिल्ली पुलिस में हैं। आयोग ने उनके इस बयान को मानने से इनकार कर दिया कि वे प्रधानमंत्री के आदेश पर किसी अन्य काम में व्यस्त थे।

रघुराज सिह: सब-इंसपेक्टर रघुराज सिह जिनका कार्य यह देखना था कि सभी सुरक्षा कर्मचारी सूची के अनुसार अपने स्थान पर हैं, अभी तक सेवा में बने हैं।

एमएल कारवाल: हत्या के कुछ महीने पहले सहायक पुलिस आयुक्त एमएल कारवाल के पास बेअंत सिह की शिकायत आयी थी, पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। वे अभी भी दिल्ली पुलिस में अपने पद पर बने हैं।

आरके शर्मा: इसी प्रकार सहायक पुलिस आयुक्त आरके शर्मा के पास भी बेअंत सिह की एक शिकायत आयी थी, पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उनकी भी पदोन्नति कर दी गयी है।

केएम महाजन: सहायक पुलिस आयुक्त केएम महाजन के पास हत्या से एक वर्ष पूर्व सतवंत सिह के तबादले का प्रस्ताव आया था जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान न देने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

हाकिम अली: एएसआई हाकिम अली के पास भी सतवत सिह के तबादले का प्रस्ताव आया था, पर उन्होंने यह प्रस्ताव रद्द कर दिया। अली अभी तक दिल्ली पुलिस में हैं।

जे खेन्दुलना: इसी प्रकार हेड-कांस्टेबल जे खेन्दुलना के पास भी सतवंत सिह के तबादले का प्रस्ताव आया था, पर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नही दिया। बाद में झूठे दस्तावेज देकर कहा कि उन्होंने प्रस्ताव को वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दिया था। खेन्दुलना अभी भी दिल्ली पुलिस में हैं।

पीसी कादियान: पीसी कादियान को आयोग ने हत्या प्रयास के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वायरलेस संदेश न भेजने का दोषी पाया था। कादियान के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

महीपाल सिह: इसी प्रकार सब-इंसपेक्टर महीपाल सिह, जिन्होंने बेअंत सिह के साथ ड्यूटी बदली, के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

नाथू सिह: निगरानी अधिकारी नाथू सिह, जिन्होंने ड्यूटी बदलने की इजाजत दी, के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

ठक्कर आयोग द्वारा अभ्यारोपित अन्य अधिकारी इतने भाग्यवान नहीं हैं।

एचडी पिल्लै: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पिल्लै को ठक्कर आयोग के गठन से पहले ही ५ नवंबर '८४ को निलंबित कर दिया गया था। ठक्कर आयोग ने भी उनको लताड़ा। पर बाद में गठित दो उच्चस्तरीय समितियों, 'बसाक कमेटी' तथा 'लोक सेवा आयोग समिति' ने उन्हें निर्दोष करार दिया। पर वे अभी तक निलंबित हैं।

जीआर गुप्ता: पिल्लै की तरह पुलिस उपायुक्त गुप्ता को भी ठक्कर आयोग के गठन से पहले ही ५ नवंबर, १९८४ को निलंबित कर दिया गया था। ठक्कर आयोग ने उनको भी लताड़ा। बाद में उनको भी 'बसाक कमेटी' तथा लोक सेवा आयोग समिति ने निर्दोष पाया, पर वे अभी तक निलंबित हैं।

इसी प्रकार सब-इंसपेक्टर एसएस चतुर्वेदी, हेड-कांस्टेबल कृष्णलाल, सहायक पुलिस आयुक्त डीसी गुलिया तथा जगदीश सिह अभी तक मुअत्तल हैं।

—अभय अग्रवाल

जब फेयरफैक्स जांच के तहत विश्वनाथ प्रताप सिंह पर विदेशी जासूसों से मिलकर देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश का हवाला दिया था, तब विपक्ष ने उसकी रिपोर्ट को आधारहीन और निरर्थक करार क्यों दिया था?

अनुत्तरित प्रश्न: किसी भी प्रधानमंत्री की हत्या का मामला राजनीतिक दांवपेंचों और निहित स्वार्थवाली अफवाहों की परिधि से बाहर होना चाहिए। यह मसला अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि श्रीमती गांधी की हत्या की वारदात को पक्ष-विपक्ष आज राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को उद्यत है। रिपोर्ट के बारे में सत्ता पक्ष द्वारा अपनायी गयी कार्यशैली ने अनंत अफवाहों को जन्म दे दिया है। अनुत्तरित प्रश्नों की झड़ी मात्र विपक्ष में ही नहीं, कांग्रेसी खेमों में भी लगायी जा रही है। रिपोर्ट पेश होने के बाद की सरकारी कार्यवाही की जानकारी से संतोष नहीं होता। सरकार ने इस बात का पता लगाने की कार्रवाई नहीं की कि इस साजिश में कौन-कौन संलिप्त थे? इस बात का भी जवाब नहीं मिलता कि एक हत्यारे बेअंत सिंह की सिक्योरिटी कक्ष में लगभग आधे घंटे बाद हत्या क्यों कर दी गयी, जबकि वह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की हिरासत में था? क्या उसका मुंह बंद करके साजिश के पर्दाफाश को रोकने के लिए ऐसा किया गया? सरकार द्वारा रिपोर्ट आने के बाद ठोस कार्रवाई का नहीं होना संदेहों को जगाता है। बीबीसी की उस खबर पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि किसी खुफिया एजेंसी ने हत्यारों से संपर्क किया था।

रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद षड्यंत्र के पर्दाफाश होने की जगह श्रीमती गांधी की हत्या का रहस्य और अधिक गहरा गया है। रिपोर्ट के ७००० से अधिक पृष्ठों को गुप्त रखने के निर्णय ने कानूनी संकट तो खड़ा कर ही दिया है। कारण, रिपोर्ट को पेश करने के पूर्व पिछले संशोधन को रद्द करने के प्रस्ताव के बाद सरकार के लिए पूरी रिपोर्ट पेश करना लाजिमी हो गया है। बशर्ते सरकार दो दिन बाद नया प्रस्ताव न ले आये। किंतु राजनीतिक संकट इससे भी अधिक गहरा है। क्योंकि मात्र विपक्ष ही नहीं, आज कांग्रेसजन भी रिपोर्ट के अंशों को गुप्त रखने की सरकारी मंशा के प्रति सशंकित हैं। कदाचित इसी से उबरने के लिए लगभग २०-२५ वरिष्ठ कांग्रेसी सांसदों की एक विशेष बैठक बुलायी गयी। गृहमंत्री बूटा सिंह, चिदंबरम और शीला दीक्षित ने इसे संबोधित किया। मुख्य लक्ष्य इन सांसदों को यह विश्वास दिलाना था कि रिपोर्ट के इन अंशों को गोपनीय रखना राष्ट्र और जन हित में है। इसी के चलते आव्हान किया गया कि वे विपक्ष का डटकर मुकाबला करेंगे। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि बूटा सिंह के इस तर्क से अनेक पार्टी सांसद न केवल असंतुष्ट रहे, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि सरकारें अपने निर्णय पर अटल नहीं रहती। अतः सदस्यों से किसी सहयोग की अपेक्षा के पूर्व सरकार कोई दोटूक फैसला ले।

सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी समस्या सुदीर्घ, सुनियोजित और सुचारू रणनीति का अभाव है। एक के बाद एक धोखा खाने के उपरांत अब राजीव गांधी छुटभैये राजनीतिज्ञों के चंगुल से निकल कर नौकरशाही के शिकंजे में जा फंसे हैं। जाहिर है

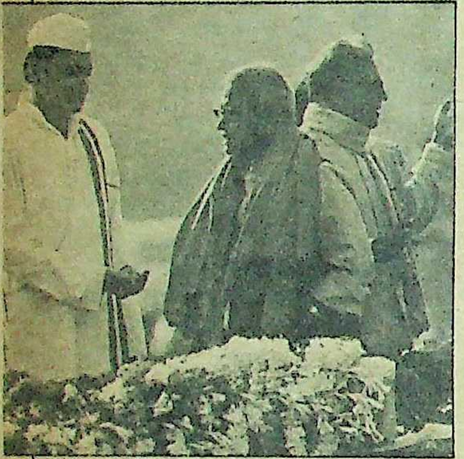
टीवी पर ऐसे दृश्यों का पुनः प्रसारण क्यों?

धवन पर संदेह

क्या आधार पर्याप्त है?

लगता है, भाग्य आरके धवन के साथ हमेशा चालें चलता रहा है। पिछले दस वर्षों के दौरान वे गिरे हैं, उठे हैं, फिर गिरे हैं, फिर उठे हैं। अबकी मर्तबा उनके विरुद्ध आरोप, जिनके चर्चे ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में हैं, बहुत ज्यादा संगीन बन गये हैं जो आनेवाले लंबे अरसे तक उन्हें लाचार बनाये रख सकते हैं। पहले वे अपनी शक्ति के स्रोत—श्रीमती गांधी—के साथ ही नीचे गिरे थे और वफादारी का मोल चुकाने को बाध्य हुए थे। इसका पुरस्कार उन्हें १९८० में, श्रीमती गांधी के दुबारा सत्ता के आने के साथ ही मिला। यह पुरस्कार धवन को राजीव गांधी का उदय होते ही खो देना पड़ा। लेकिन सत्ता के गलियारे से वे सजायाफ्ता गुनहगार की तरह नहीं, बल्कि एक शहीद की तरह निकले थे।

लेकिन अब ठक्कर आयोग ने एक तरह से 'धवन को फांसी के फंदे पर लटका दिया' है। धवन कहते भी हैं कि जस्टिस ठक्कर ने उन्हें फांसी पर चढ़वाने का प्रयास किया है। एक अच्छे न्यायविद की भांति ठक्कर ने धवन को संदेहों के घेरे में लाते हुए तर्क भी दिये हैं। लेकिन, चूंकि आयोग द्वारा पूछे गये सवालात ही (धवन के जवाब नहीं) सुलभ हैं, इसलिए यह कहना कठिन है कि जांच के दौरान जो सबूत और बयान प्रस्तुत किये गये, वे धवन को दोषी करार देने और श्रीमती गांधी के प्रति उनकी निष्ठा पर संदेह करने के लिए पर्याप्त हैं।

जो परिस्थितियां न्यायमूर्ति ठक्कर के संदेहों का आधार बनी हैं वे इस प्रकार हैं:

संदेह के कारण: (जो रिपोर्ट में दर्ज हैं)	संभावना
◆ धवन ने हत्यावाली सुबह पीटर उस्तीनोव के टीवी दल से श्रीमती गांधी की मुलाकात का समय, बगैर किसी को बताये सुबह ८.३० बजे से बदलकर ९.०० बजे कर दिया।	◆ अकसर मुलाकातों का समय आगे-पीछे सरका दिया जाता है, जिसका कारण दर्ज नहीं किया जाता। ऐसा हर कहीं होता है, खासकर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ। फिर, समय बदल जाने से हत्यारों को सहूलियत कैसे हुई? इस प्रश्न का कोई तर्कसंगत उत्तर ठक्कर आयोग ने नहीं दिया है।
◆ आपरेशन ब्ल्यू स्टार के बाद सिख गार्डों को श्रीमती गांधी की अंदरूनी सुरक्षा से हटा दिया गया था, पर धवन ने फिर उन्हें पूर्ववत तैनात कराया।	◆ सिख गार्डों को तैनात किये जाने के लिए एक राजनीतिक फैसला हुआ था, ताकि यह दिखाया जाये कि सभी सिख क्षुब्ध नहीं हैं, न ही सभी सिख संदेहास्पद हैं।
◆ धवन ने आयुर्विज्ञान संस्थान के वायरलेस का उपयोग कर पूछा कि हत्यारों का क्या हुआ?	◆ यह (तत्कालीन स्थिति में) एक अधिकारी की सामान्य जिज्ञासाजनित चेष्टा भी हो सकती थी कि वह इस बात की जानकारी ले कि हमलावर पकड़े गये या नहीं। ऐसी दर्याफ्त से धवन के दोषी होने के नतीजे तक कैसे पहुंचा जा सकता है? वे हत्यारों का कुशल-क्षेम तो पूछ नहीं रहे थे।

इनकी (नौकरशाही) भी सलाह राजनीति के यथार्थ से कहीं दूर और किताबी होती है। अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि तदर्थवाद के तहत कदम उठाने के लिए विख्यात राजीव गांधी आज अपना हर कदम सांसतग्रस्त होकर उठाने को मजबूर हैं। नतीजतन भूल दर भूल होती जा रही है। इसके ठीक विपरीत विपक्ष अकस्मात मिले इस मुद्दे को भरपूर इस्तेमाल करने का न केवल आकांक्षी है, बल्कि इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से पहलकदमी भी कर रहा है। विपक्षी रणनीति दोहरी है। एक तो, पूर्ण रिपोर्ट पेश करने की मांग के लिए निरंतर दबाव बनाये रखना। दूसरे, रिपोर्ट के आधार पर सरकार की नीयत के प्रति संदेह को बरकरार रखना और तीसरे यह उजागर करना कि सरकार कितनी अक्षम, अयोग्य, अकर्मण्य है। इस रस्साकशी में अंततः विजयश्री किसको मिलेगी?

विपक्ष का दावा है कि सरकार के पास अंततः पूर्ण रिपोर्ट पेश करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहेगा। जयपाल रेड्डी के अनुसार, "राजीव गांधी दोहरी चोट खायेंगे। वे रिपोर्ट का कोई भी अंश दबाने में असमर्थ रहेंगे और जितने दिन इसे रोके रखने का प्रयास करेंगे, उतने दिन अपने बारे में सांघातिक संदेहों का बीजारोपण करेंगे। "जैसे-जैसे संदेहों का यह दायरा बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री की सरकार और पार्टी पर पकड़ कमजोर होना, आश्चर्यजनक न होगा। पर्यवेक्षकों के अनुसार इस समय एकमात्र यही रास्ता बचा है कि सरकार सच्चाई को ढांकने-मूंदने की जगह उसकी तह में जाकर अपने पाक दामन होने का सबूत पेश करे। इसके लिए यदि पुनः जांच आयोग बिठाना पड़े, किसी की बलि चढ़ानी पड़े, तो उसके लिए भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी किये बिना जनता की अदालत में उसके हक में फैसला नहीं हो सकता। आगामी चुनावों में श्रीमती गांधी की हत्या और उसकी जांच की भूमिका पर बातचीत करते हुए कांग्रेस-एस सांसद किशोर चंद देव ने 'माया' से कहा, "यह सरकार श्रीमती गांधी की शहादत के मुद्दे पर सत्तारूढ़ हुई थी। आज इसी मुद्दे पर वह सांसत में पड़ गयी है और अगलें चुनावों में इसी मुद्दे पर वह बर्खास्त कर दी जायेगी।"

रिपोर्ट के आने के बाद केहर सिंह के पुत्र राजिंदर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अनुरोध किया है कि उसे एक निर्दोष बाप का बेटा घोषित किया जाये और हर्जाने के रूप में १० लाख रुपए दिलवाये जायें, क्योंकि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से यह जाहिर हो गया है कि श्रीमती गांधी की हत्या के षड्यंत्र में उसका पिता नहीं, स्वयं राजीव गांधी और आरके धवन शामिल थे। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह चुनाव वर्ष है और चुनावों में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों पर उठी संदेह की उंगलियों को हटाना अनिवार्य है।

इसमें कोई शक नहीं कि ठक्कर रिपोर्ट का मुद्दा निर्णायक भूमिका निभायेगा, कदाचित यह बात कांग्रेस भी समझ गयी है। इसको भुनाने का कोई भी अवसर वह भी गवाना नहीं चाहेगी। तो क्या श्रीमती गांधी की हत्या मात्र राजनीतिक दांवपेंच का हिस्सा बनकर रह जायेगी?

—रंजना कक्कड़, त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

◆ बेअंत सिंह की चिट्ठियों में धवन का नाम कई बार आया है।	◆ बेअंत सिंह लंबे अरसे से श्रीमती गांधी के साथ रहा। धवन भी हमेशा श्रीमती गांधी के साथ रहे। संभवतः बेअंत सिंह धवन को अच्छी तरह जानता था और समय-समय पर उनसे मदद-सहूलियत भी मांगता था (लिहाजा उसके पत्र में धवन का नाम आना सामान्य बात भी हो सकती है)।
◆ सतवंत सिंह ने कहा था कि बेअंत सिंह ने उसे हिदायत दी थी कि धवन को चोट न पहुंचे।	◆ चूंकि बेअंत, धवन को अपना पक्षधर पाता था, अतः संभव है इसी कारण उसने सतवंत सिंह को यह हिदायत दी हो। उसका निशाना श्रीमती गांधी थीं और यदि वह अपनी कार्रवाई को पवित्र मानता था, तो एक बेगुनाह को मार कर उसे नापाक अंजाम कैसे दे सकता था?
◆ जब गोली चल रही थी, तब धवन नीचे की ओर देख रहे थे और जब श्रीमती गांधी मरीं, धवन ने उन्हें बचाने की परवाह नहीं की।	◆ धवन जब भी श्रीमती गांधी के साथ रहते थे, तब नीचे ही ताकते थे, क्या इस संभावना को नकारा जा सकता है? उन्होंने फौरन बचाने की चेष्टा नहीं की, ऐसा इस कारण भी हो सकता है, क्योंकि वे स्तब्ध रह गये और श्रीमती गांधी पर गोली दागी जाने की आवाज ने उन्हें हक्का-बक्का बना दिया था। जिस प्रकार से धवन को परेशान किया जा रहा था, वैसी हालत में कोई भी अपने विवरण में (बयान) संशोधन कर सकता था या कुछ जोड़ सकता था।
◆ धवन ने दो बार बयान बदले (जिसे ठक्कर आयोग ने इस संदेह का आधार माना कि धवन अपने बचाव की कोशिश कर रहे हैं): (१) पहले उन्होंने कहा कि सिख गार्डों की फिर से तैनाती उन्होंने श्रीमती गांधी के कहने से करायी, इसके विपरीत उन्होंने दूसरी बार कहा कि उन्होंने सिख गार्डों को फिर से 'नियुक्त न करने' का निर्देश दिया था। (२) पहले धवन ने माना कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को जानते थे, पर बाद में ३१ अक्तूबर, १९८४ के घटनाक्रम का विवरण देते हुए कहा कि उन्होंने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के नाम घटना के बाद ही जानें।	◆ यह भी हो सकता है कि शुरू में उन्होंने अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों को प्रभावित करनेवाले कुछ तथ्य छिपाने चाहे हों।

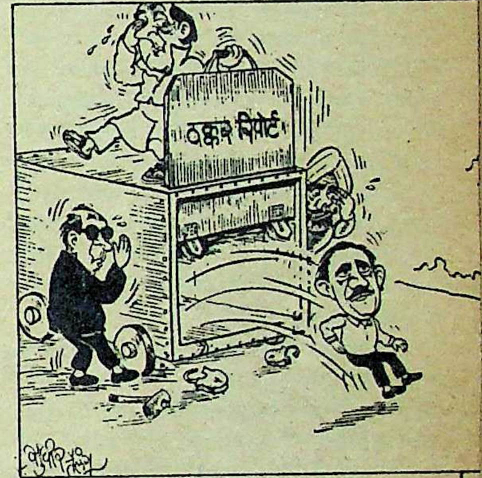

'नवभारत टाइम्स' से साभार

शक की सुई ठक्कर पर

इंडियन एक्सप्रेस को ठक्कर आयोग की रिपोर्ट किसके माध्यम से प्राप्त हुई, इस सवाल को लेकर अब तरह-तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं। जहां एक ओर प्रधानमंत्री राजीव गांधी तथा उनकी टीम के नये तथा वरिष्ठ लोग इस बात को हवा दे रहे हैं कि हो न हो ठक्कर आयोग की रिपोर्ट अरुण नेहरू के माध्यम से एक्सप्रेस को पहुंची, वहीं विधि विशेषज्ञ अरुण जेतली ने अरुण नेहरू की ओर से 'हिंदुस्तान टाइम्स' को मानहानि की नोटिस दी है और कहा है कि एक्सप्रेस समूह को रिपोर्ट देनेवाले अरुण नेहरू नहीं हैं। यही नहीं, जब इस संबंध में 'माया' ने जेतली से संपर्क किया, तो वे बोले, "अरुण नेहरू के नाम को उछालना पूरी तौर पर काल्पनिक तथा आधारहीन है। सच तो यह है कि अरुण शौरी के पास पहुंचने से पहले तो किसी को रिपोर्ट के संबंध में गुमान तक नहीं था।"

जहां तक कांग्रेस के नये प्रचार का सवाल है, तो कांग्रेसी खेमे में तो यह बात लगभग सभी की जुबान पर है कि न्यायमूर्ति एमपी ठक्कर की अरुण नेहरू से साठगांठ है। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान राजीव गांधी ने खुद इस बात पर जोर दिया कि अरुण नेहरू के सिवा और कोई रिपोर्ट लीक नहीं कर सकता। इसी नतीजे पर आरके धवन भी पहुंचे हैं। उनका भी यही संदेह है कि अरुण नेहरू ने ही ठक्कर रिपोर्ट लीक की है। उनका मानना है कि बहुत पहले से ही एमएल फोतेदार और स्वर्गीय वीएस त्रिपाठी से तालमेल बिठाकर उन्हें श्रीमती गांधी और राजीव गांधी के समक्ष अरुण नेहरू और अरुण सिंह, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि उन्हें तब सफलता नहीं मिली, इसलिए अब जब राजीव गांधी ने पुनः उनको अपने करीब किया, तो अरुण नेहरू ने ठक्कर रिपोर्ट एक्सप्रेस समूह को सौंपकर उन्हें बदनाम किया।

नजर अपनी-अपनी: राजीव गांधी और आरके धवन तो जो मान रहे हैं सो है ही, कल्पनाथ राय तो इन दोनों से भी चार कदम आगे हैं। उनके अनुसार, "सब जानते हैं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट अरुण नेहरू के निर्देशन में तैयार हुई थी, टाइप की गयी थी और छह महीने उन्हीं के पास थी। अरुण नेहरू ने जस्टिस ठक्कर को विश्वास में ले लिया था।" कल्पनाथ राय इस बात पर जोर देते हैं कि फोतेदार और पीसी एलेक्जेंडर मिलकर धवन को निकलवाना चाहते थे। "सच तो यह है कि अरुण नेहरू ने ठक्कर को विश्वास में लेकर दबाव डाला कि वे श्रीमती गांधी हत्याकांड के षड्यंत्र में आरके धवन को भी लपेट लें," कल्पनाथ राय कहते हैं। यह सच है कि राजीव गांधी ने फिलहाल इतना खुलकर अरुण नेहरू को नहीं घसीटा है, किंतु उन्होंने हाल में एक वरिष्ठ सांसद को बताया था कि उन्होंने (राजीव गांधी) खुद ठक्कर आयोग की रिपोर्ट की तीन कापियां रक्षा मंत्रालय की आलमारी में बंद की थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि अरुण नेहरू के सिवा दूसरा कोई रिपोर्ट की कापियां हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकता। वह तो कहिए कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गयी थी और अरुण नेहरू ही उस समय राजीव गांधी के करीब थे, वरना तत्कालीन गृहमंत्री एसबी चह्वाण भी संदेह के घेरे में आ जाते।

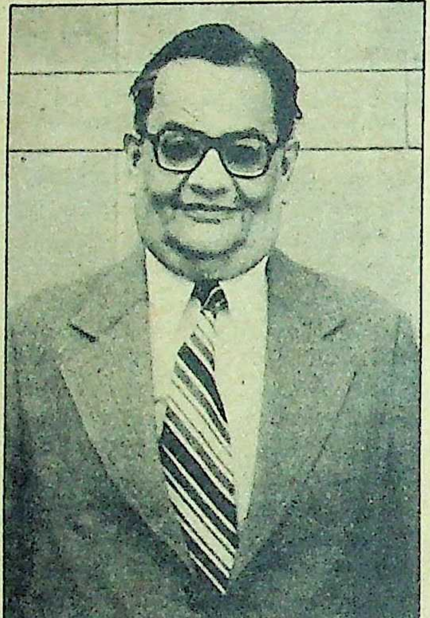

कांग्रेसियों का कुफ्र: एमपी ठक्कर

'हिंदुस्तान टाइम्स' के अलावा 'संडे' पत्रिका ने भी नेहरू पर ही संदेह व्यक्त किया है। पत्रिका में लिखा गया है कि इस बार राजीव गांधी पर प्रहार करने के लिए रामनाथ गोयनका और अरुण नेहरू ने हाथ मिलाया और आरके धवन को निशाना बनाकर ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के अंशों को प्रकाशित कर दिया। पत्रिका में यह भी लिखा गया है कि अरुण नेहरू आरके धवन से डरते हैं। कहा जाता है कि शुरू में अरुण नेहरू ने आरके धवन को अपने साथ करने का प्रयास किया, ताकि वे राजीव गांधी के खिलाफ धवन का इस्तेमाल कर सकते, किंतु धवन उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुए। इससे रुष्ट होकर नेहरू ने धवन की ही जड़ उखाड़ने की कसम खा ली।

ठक्कर पर शक: असलियत जो भी हो, फिलहाल तो स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संकट को दूर रखने के लिए जस्टिस ठक्कर की निष्ठा और नीयत को निशाना बना लिया है। बकौल अरुण जेतली, "अजीब हाल है, जो सरकार इससे पहले जस्टिस ठक्कर पर बेइंतहा विश्वास करती थी, आज वही सरकार तथा उसके प्रतिनिधि इस बात की कोशिश में लगे हैं कि जस्टिस ठक्कर को राजनीतिक रूप से बेईमान करार दिया जाये।" धवन की वापसी तथा रिपोर्ट के प्रकाशन से पूर्व न्यायमूर्ति ठक्कर पर उंगली उठाने की किसी ने जुर्रत नहीं की थी। ठक्कर रिपोर्ट पूरी होने के बाद जस्टिस ठक्कर को फेयरफैक्स आयोग की बागडोर थमा दी गयी थी और बाद में उन्हें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किंतु आज जब समीकरण बदल गया है, तो कांग्रेसी उन पर संदेह भरी निगाह उठाते नहीं सकुचा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वास्तव में जस्टिस ठक्कर ही वर्तमान संकट के महत्वपूर्ण कारण हैं। उनके साथ कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी साथियों को भी घसीटा जा रहा है।

शिवशंकर के संबंध: दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में यह अफवाह विश्वास हासिल करती जा रही है कि मानव संसाधन विकास मंत्री पी शिवशंकर ने बिल्ली को आजाद किया है। शिवशंकर पर राजफाश करने का संदेह इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेसी जानते हैं कि शिवशंकर और ठक्कर के वर्षों से घनिष्ठ संबंध हैं। इस संबंध में राजीव गांधी के पूर्व सहायक का कहना है, "यह सच है कि शिवशंकर और फोतेदार जस्टिस ठक्कर को श्रीमती गांधी हत्याकांड के बारे में जानकारी देते थे।" यही नहीं 'संडे' पत्रिका में तो इस बात पर जोर दिया गया है कि अरुण नेहरू और पी शिवशंकर के बीच भी अच्छे संबंध थे। इन धारणाओं से यह शक हो सकता है कि ठक्कर रिपोर्ट में या तो नेहरू तथा शिवशंकर दोनों ने या किसी एक ने अपना नजरिया डलवाया होगा। ऐसे में यह भी संभावना बनती है कि शिवशंकर ने रिपोर्ट लीक की हो। किंतु सवाल यह है कि शिवशंकर को रिपोर्ट मिली कैसे होगी? कानूनी एतबार से तो किसी आयोग से संबंधित न्यायमूर्ति को जांच रिपोर्ट की एक कापी अपने पास रखनी चाहिए। इसलिए जाहिर है कि जस्टिस ठक्कर के पास भी रिपोर्ट की कापी मौजूद है। मौजूदा समय में कहानी जिस तरह से बुनी जा रही है, उस हिसाब से तो यह लगता है कि ठक्कर ने अरुण नेहरू और पी शिवशंकर या दोनों में से एक के कहने पर धवन को षड्यंत्र में घसीटा होगा। अब जब धवन पुनः वापस आये, तो

इन तीनों को विशेषकर जस्टिस ठक्कर को अपनी स्थिति संकट में नजर आयी होगी और उन्होंने रिपोर्ट लीक करके इस संकट से बचने की कोशिश की होगी। एक न्यायमूर्ति के लिए ऐसी बात कहना अन्याय है, लेकिन भारतीय राजनीति में सब कुछ जायज है।

ऐसी खबर है कि धवन की वापसी के बाद उस कमरे की पुताई रोक दी गयी, जहां जस्टिस ठक्कर को विधि आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से काम संभालना था। यह जरूरी नहीं है कि यह रुकावट धवन की शह पर की गयी, किंतु जस्टिस ठक्कर के लिए संकट की सूचना यह अवश्य थी।

जस्टिस ठक्कर के प्रति धवन के रवैये का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब रिपोर्ट आयी, तो धवन ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से 'धवन को सूली पर चढ़ाने की' रिपोर्ट कहा।

आज स्थिति यह है कि २७ मार्च को ठक्कर रिपोर्ट सदन में पेश करने के बाद कांग्रेस पार्टी तथा हाईकमान की जुबान पर बस एक बात है कि जस्टिस ठक्कर ने राजफाश किया। जाहिर है, उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। धवन को पाकसाफ दिखाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच को महत्व देना भी जरूरी है। इसीलिए जहां कांग्रेस ने धवन को संदेह में घसीटनेवाली ठक्कर रिपोर्ट सदन में पेश की, वहीं इस बात पर भी जोर दिया कि 'विशेष जांच दल' ने अपनी खोजबीन के दौरान धवन को निर्दोष पाया।

असलियत जो भी हो, यह कहना गलत न होगा कि जस्टिस ठक्कर बदकिस्मती से राजनीति के शिकार हो गये हैं।

असलियत क्या है ? : वैसे न्यायमूर्ति ठक्कर के एक साथी का कहना है कि जस्टिस ठक्कर को कांग्रेस पार्टी से भावनात्मक लगाव शुरू से रहा है। उनके एक दूसरे जाननेवाले का कहना है कि जस्टिस ठक्कर आज भी श्रीमती गांधी काल की काफी सराहना करते हैं। यह भी खबर है कि जस्टिस ठक्कर ने शाह आयोग का विरोध किया था और वे आपातकाल के भी समर्थक माने जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि संजय गांधी के निधन पर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अवकाश भी घोषित किया था। कांग्रेस के इतना करीब रहे व्यक्ति पर आज यह आरोप है कि उसने अरुण नेहरू के दबाव में आकर आरके धवन पर संदेह किया, अजीब लगता है। सवाल यह भी है कि जब अरुण नेहरू और जस्टिस ठक्कर की सांठगांठ जगजाहिर थी, तो उन्हें फेयरफैक्स आयोग का नेतृत्व क्यों सौंपा गया ? जाहिर है, आज जिस तरह से उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि राजीव गांधी, फोतेदार, शिवशंकर, बूटा सिह तथा उनके अन्य सलाहकार इस तथ्य से वाकिफ थे। १९८६ में जब ठक्कर को फेयरफैक्स आयोग के लिए चुना गया था, तो ये सभी मौजूद थे।

फिलहाल जस्टिस ठक्कर दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित शास्त्री भवन की सातवीं मंजिल में सन्न बैठे हैं। बीच-बीच में विधि आयोग से उनके इस्तीफे की खबरें भी उड़ रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो करना था, उन्होंने किया, बाकी ईश्वर के हाथ है। किंतु ऐसा लगता है कि कांग्रेसी ईश्वर का काम खुद करना चाहते हैं। ताज्जुब है कि जो लोग अब तक उन्हें अपना समर्थक मानते थे, वही आज समीकरण बदलने से उन्हें अपना दुश्मन मान रहे हैं। अराजक अटकलों की स्थिति यह है कि कुछ राजनेता और विधिवेत्ता यहां तक कह रहे हैं कि पहले धवन को अपने से दूर और खामोश रखने के लिए राजीव गांधी ने ही ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का ठक्कर को निर्देश दिया था और अब जब स्थिति डावांडोल देखकर धवन को वापस लाना कांग्रेस की मजबूरी हो गयी तथा धवन के संबंध में संदेह सार्वजनिक हो गया, तो कांग्रेस ही ठक्कर को संदेह की स्थिति में खड़ा कर रही है। अरुण जेतली का भी ऐसा ही मानना है।

असलियत जो भी हो, यह कहना गलत न होगा कि जस्टिस ठक्कर बदकिस्मती से राजनीति के शिकार हो गये हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने राजनीतिक संबंध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगीं। ●

विवादों से घिरे न्यायमूर्ति ठक्कर आखिर हैं कौन ?

भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में न्यायमूर्ति मनहरलाल प्राणलाल ठक्कर एक सामान्य नाम मात्र ही रहे होते, किंतु गांधी-परिवार के संदर्भ में वे कई बार सुर्खियों में रहे हैं।

पहला धमाका जून १९८० में तब हुआ जब गुजरात उच्चन्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने संजय गांधी की मृत्यु के शोक में एक दिन के लिए न्यायालय बंद करने का आदेश दिया। वह अपने में एक अभूतपूर्व आदेश था, क्योंकि संजय गांधी न तो कोई राजनीतिक हस्ती थे और न राष्ट्रीय विभूति। नतीजतन सुर्खियों में आना लाजिमी था। तभी से गांधी परिवार का 'जज' होने का उन पर छापा भी लगा।

न्यायमूर्ति ठक्कर का न्याय और उसकी प्रक्रियो से यद्यपि पुराना संबंध है, किन्तु न्यायाधीश के रूप में नहीं। शुरुआत उन्होंने सौराष्ट्र उच्चन्यायालय (गुजरात उच्चन्यायालय का पुराना नाम) में एक एडवोकेट के रूप में की। ८ वर्षों तक एक सामान्य एडवोकेट के रूप में कार्यरत रहने के पश्चात वे कुछ समय के लिए बंबई उच्चन्यायालय में चले गये। न्यायविद के रूप में उन्होंने १९६३ में सिटी सिविल ऐंड सेशन कोर्ट जज के रूप में पहला फैसला सुनाया। उच्चन्यायालय में उनका प्रवेश १९६९ में एडिशनल जज के रूप में हुआ। स्थायी जज के रूप में उनकी बहाली १९७२ में हुई और १९८१ में वे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। मात्र दो वर्ष बाद ही उनका आगमन दिल्ली में हुआ। तब से वे लगातार सुर्खियों में रहे हैं और आज उनका नाम बच्चे-बच्चे की जबान पर है।

सुर्खियों में रहने की पहली वजह उनका इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना रहा है। उसके बाद बारी आयी फेयरफैक्स जांच आयोग की। यद्यपि इस आयोग में वे न्यायमूर्ति नटराजन के साथ संयुक्त अध्यक्ष थे। किंतु विवाद के घेरे में न्यायमूर्ति ठक्कर ही अधिक रहे। कारण गांधी परिवार का जज करार दिया जाना, साथ ही इंदिरा गांधी हत्याकांड में अपनी रिपोर्ट द्वारा सरकार को प्रसन्न करने का कथित आरोप।

फेयरफैक्स का उबाल तो कुछ ठंडा पड़ गया। किंतु इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच आयोग में प्रस्तुत रिपोर्ट के हाल के प्रकाशन ने न केवल न्यायमूर्ति ठक्कर को सुर्खियों में ला दिया, बल्कि न्यायमूर्ति ठक्कर और सरकार को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक नहीं दो बार न्यायमूर्ति ठक्कर के नाम का भरपूर इस्तेमाल किया। पहली बार जब धवन को हटाया गया, तो दलील यह दी गयी कि इसकी सिफारिश स्वयं न्यायमूर्ति ठक्कर ने की थी। दूसरी बार संसद में इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच रिपोर्ट को न पेश करने का जो निर्णय सरकार ने लिया, उसके पीछे भी न्यायमूर्ति ठक्कर की सिफारिश का हवाला दिया गया।

न्यायमूर्ति ठक्कर को निकट से जानने वाले यह स्वीकार नहीं करते कि उन्हें सरकार अथवा किसी अन्य द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन उनकी रिपोर्ट पर आधारित वर्तमान बवंडर के पश्चात उन्होंने एक अच्छे न्यायाधीश की तरह अपने होंठ सिल लिये हैं।

—रंजना कक्कड़

माया विशेष

गुनहगार धवन बेगुनाह !

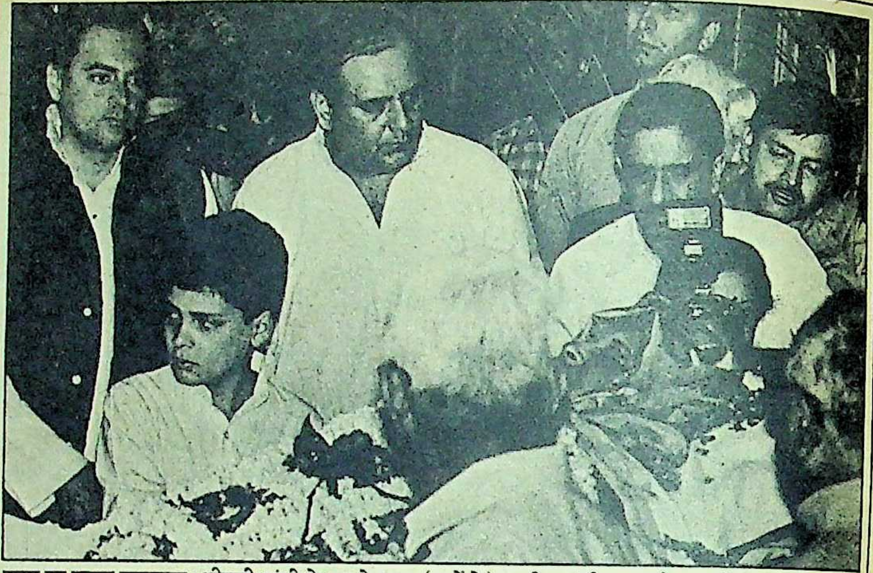

हत्या का रहस्य बरकरार : श्रीमती गांधी के शव के साथ (बायें से) राजीव गांधी, अरुण नेहरू और धवन

इस बात में संदेह नहीं कि राजीव गांधी सरकार का भविष्य तथा आगामी चुनाव में उसकी सफलता इस सवाल के उचित उत्तर पर निर्भर करेगी कि किस तरह १५ नवंबर, १९८४ को कायम की गयी स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) ने पहले तो ठक्कर आयोग को इस निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता की कि धवन दोषी हैं और बाद में खुद ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ठक्कर की छानबीन को रद्द करते हुए आरके धवन को निर्दोष घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती गांधी हत्याकांड की छानबीन के लिए कमीशंस आफ इनक्वायरी एक्ट १९५२ (६० आफ १९५२) की धारा ३ के अंतर्गत २० नवंबर, १९८४ को ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। जबकि एसआईटी का गठन ठक्कर आयोग के गठन से पांच दिन पूर्व किया गया था, जिसका नेतृत्व महानिदेशक श्रेणी के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंदराम कर रहे थे। उनके साथ एक आईजी, तीन डीआईजी, तीन एसपी तथा पचास अन्य अधिकारी छानबीन में लगाये गये थे।

एसआईटी ने अपनी छानबीन के प्रथम चरण में नामजद हत्यारों तथा प्रत्यक्ष रूप से हत्या में शामिल लोगों की असलियत जानने का काम किया और बाद में हत्या से संबंधित षड्यंत्र की खोजबीन का काम शुरू किया।

ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में संदेह की सुई आरके धवन की ओर होने से तो ऐसा लगता है कि ठक्कर आयोग ने अपना ज्यादा समय और ज्यादा ध्यान इस बात का पता चलाने में लगाया कि वास्तव में हत्या के षड्यंत्र में आरके धवन की क्या भूमिका थी? स्वाभाविक है, जब एसआईटी का गठन ठक्कर आयोग के गठन से पूर्व हुआ था तथा एसआईटी प्रमुख रूप से पुलिस अधिकारियों की टीम थी, तो एसआईटी ने ठक्कर आयोग की मदद जरूर की होगी। श्रीमती गांधी हत्याकांड के बाद जांच दल जिस तरह से आरके धवन को संदेह के घेरे में ले रहे थे, उसके तहत आरके धवन से संबंधित लोगों तथा कागजात की सख्ती से जांच होना स्वाभाविक था। खबर तो यहां तक थी कि धवन के १, अकबर रोड स्थित कार्यालय, संसद भवन स्थित कार्यालय तथा साउथ ब्लाक स्थित कार्यालय की तलाशी ली गयी थी तथा तलाशी के दौरान पाये गये कागजात की (जिन पर संदेह था) पीसी एलेक्जेंडर द्वारा गौर से छानबीन की गयी।

जांच के समय रुख : इसलिए यदि कोई यह कहता है कि आरके धवन को शुरू में एसआईटी तथा ठक्कर आयोग ने मिलकर संदेह के घेरे में खड़ा किया, तो गलत न होगा, क्योंकि उस दौरान आरके धवन के बयानात तथा उनकी व्याख्याओं की प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात अन्य लोगों से पुष्टि की जाती थी तथा उनकी सत्यता जानने का प्रयास किया जाता था। उस दौरान आरके धवन को कई-कई घंटे सवाल-जवाब के दौर से गुजरना पड़ा था तथा उनके कार्यालयों से नियुक्ति तथा तैनाती से संबंधित जो भी दस्तावेज हासिल किये गये थे, उनकी उनसे विस्तृत जानकारी ली जाती थी। इस संबंध में एक सूत्र का तो यहां तक कहना है कि धवन से यह भी पूछा जाता था कि उन्होंने फलां-फलां को मिलने के लिए क्यों बुलाया था तथा फलां व्यक्ति को मिलने के लिए दिन में न बुलाकर रात में क्यों बुलाया था? विश्वस्त सूत्रों से मिली खबर के अनुसार एसआईटी के कुछ अधिकारियों को धवन पर पूरा संदेह था तथा उन्हें विश्वास हो गया था कि धवन श्रीमती गांधी से संबंधित राज की बातों को बाहर पहुंचा रहे थे। एसआईटी के कुछ अधिकारियों को तो यह भी शक हो गया था कि धवन संदेहास्पद चरित्र के लोगों के काफी करीब थे। इसीलिए उन अधिकारियों ने धवन के निजी तथा सरकारी जीवन की बखिया उधेड़ डाली थी और वे पूरी कोशिश में थे कि कहीं से कोई मजबूत सुराग हाथ लग जाये। स्थिति यह थी कि धवन के व्यापारी दोस्तों तथा अन्य जाननेवालों से भी पूछताछ की गयी थी।

कुछ सूत्रों का कहना है कि नामीगिरामी अखबार समूहों से जुड़ी दो महिला पत्रकारों, एक स्वतंत्र महिला पत्रकार, एक सांसद की बेटी तथा नामीगिरामी कांग्रेसी नेता की एक तलाकशुदा बेटी का नाम धवन के दोस्तों की सूची में जोड़ा गया था। यही नहीं, इन महिलाओं में से कुछ से तो पूछताछ भी की गयी थी। खासतौर से समाचार-पत्रों से जुड़ी महिला पत्रकारों से काफी पूछताछ की गयी। उनसे यह पूछा गया था कि वे धवन को कितने नजदीक से जानती हैं और अकसर उनसे क्यों मिलती हैं? यही नहीं, इन महिलाओं से यह भी पूछा गया था कि क्या वे धवन को खुफिया दस्तावेज लाकर देती हैं या धवन से ले जाकर किसी और को देती हैं? सूत्र का कहना है कि ये सवाल शायद इसलिए पूछे गये थे, क्योंकि आईएस बिंद्रा और धवन के संबंधों का सुराग एसआईटी को मिल गया था। उल्लेखनीय है कि आईएस बिंद्रा राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के सचिव थे, जिन्हें राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध पंजाब कैडर में वापस भेज दिया गया था। धवन और बिंद्रा के संबंधों का सुराग मिलने पर यह संदेह किया जा रहा था कि उन दोनों के सिर्फ कार्यालयी संबंध नहीं थे, अलबत्ता दोनों में काफी बनती थी। यह भी कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि दोनों महिला पत्रकार ज्ञानी जैल सिंह तथा बिंद्रा से क्यों मिलती थीं? इसी आधार पर यह माना जा रहा था कि बिंद्रा को प्रधानमंत्री कार्यालय की बहुत सी खुफिया तथा सनसनीखेज बातों की जानकारी, धवन अथवा महिला पत्रकारों के माध्यम से विभिन्न मौकों पर मिलती थी। उल्लेखनीय है कि श्रीमती गांधी भी ज्ञानी जैल सिंह को शक की नजर से देखने लगी थीं तथा कई मौकों पर उन्होंने जैल सिंह के पंजाब में अनावश्यक हस्तक्षेप पर गुस्सा भी जाहिर किया था। इसलिए एसआईटी को यह संदेह था कि बिंद्रा धवन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अनजाने में सही, बहुत सी खुफिया बातें दोस्त के नाते बिंद्रा को बता देते थे।

धवन की पैरवी और विरोध : श्रीमती गांधी की हत्या के बाद आरके धवन के संबंधों की कड़ी-से-कड़ी जोड़ने का जो काम विशेष जांच दल (एसआईटी) ने किया सो किया, आजकल तो यह खबर भी गर्म है कि जिस दौरान धवन से पूछताछ चल रही थी, उस वक्त एक स्वतंत्र महिला पत्रकार तथा सांसद की बेटी ने वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनेताओं से मिलकर धवन के साथ किये जा रहे व्यवहार की आलोचना की थी तथा उनसे विनती की थी कि वे

हस्तक्षेप करके धवन को संदेह के घेरे से बाहर करवायें। यही नहीं, यह भी चर्चा है कि वरिष्ठ नामीगिरामी कांग्रेसी नेता की तलाकशुदा बेटी के घर उस दौरान धवन के दोस्तों की बैठकें होती थीं, जिनमें धवन को संदेह से उबारने की रणनीति तैयार की जाती थी। दूसरी ओर राजीव गांधी के लोग धवन के खिलाफ चक्रव्यूह बुनने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे थे। सूत्र का कहना है कि राजीव गांधी के सहायक उस दौरान ठक्कर आयोग की जांच से इतना चिंतित नहीं थे। उन्हें तो बस एक ही फिक्र थी कि एसआईटी किस नतीजे पर पहुंचती है? इसी सूत्र का कहना है कि एक दिन साउथ ब्लाक में सिर्फ इस बात को लेकर हंगामा मचा था कि एसआईटी में एक ऐसा वरिष्ठ अधिकारी है जो धवन का बहुत करीबी है तथा उसकी मौजूदगी असलियत का पता लगाने में बाधा बन सकती है। सूत्र का यह भी कहना है कि बाद में उस अधिकारी को टीम से हटा दिया गया था, किंतु धवन-विरोधी आज भी यह मानते हैं कि जब तक वह अधिकारी एसआईटी से जुड़ा रहा, उसने धवन की भरपूर मदद की। जबकि सचाई यह है कि जिन लोगों को एसआईटी में शामिल किया गया था, उनकी अरुण सिंह तथा वीएस त्रिपाठी द्वारा काफी जांच-पड़ताल की गयी थी और जब यह तय हो गया था कि उनमें से किसी का धवन से कभी कोई संपर्क नहीं था, तभी हरी झंडी दी गयी थी।

जहां तक एसआईटी के प्रमुख आनंदराम का सवाल है, उनकी कार्यक्षमता और ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने तथा उनके सहयोगियों ने धवन को किसी मौके पर बख्शा नहीं। बाद में न्यायमूर्ति ठक्कर ने धवन से सिख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, बेअंत सिंह के प्रति उनके लगाव, पीटर उस्तीनोव द्वारा की जानेवाली शूटिंग का समय बदलने का कारण आदि विषयों पर व्यापक पूछताछ की। यही नहीं, प्रधानमंत्री निवास में तैनात (उपायुक्त पुलिस) जीआर गुप्ता से भी इन विषयों पर अलग पूछताछ की गयी तथा उनके और धवन के जवाबों का गहरायी से अध्ययन किया गया। कहा जाता है कि धवन और जीआर गुप्ता के बयानों के आधार पर ही ठक्कर ने धवन पर संदेह किया। उल्लेखनीय है कि जब धवन से सिख सुरक्षाकर्मियों की पुनः तैनाती पर सवाल किया गया, तो उनका जवाब था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के आदेश पर सुरक्षा-इंचार्ज को निर्देश दिया था। जब यही सवाल जीआर गुप्ता से किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आरके धवन ने सिख सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति पर यह कहकर नाराजगी व्यक्त की थी कि प्रधानमंत्री खुद सिख सुरक्षाकर्मियों के तैनात न किये जाने पर नाराज हैं। अपने जवाब के दौरान गुप्ता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, "धवन ने मुझसे कहा था कि प्रधानमंत्री चाहती हैं कि सिख सुरक्षाकर्मियों को प्रधानमंत्री निवास के विशिष्ट स्थानों पर वापस बुलाया जाये।" उस दौरान गुप्ता ने यह भी बताया कि धवन चाहते थे कि खास अवसरों पर सिख सुरक्षाकर्मियों को विशेष स्थानों पर तैनात किया जाये। लेकिन धवन ने इन बातों से इनकार किया था। उनका कहना था कि उन्हें सुरक्षाकर्मियों की तैनाती से क्या लेना-देना था? उनके अनुसार उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। इस संबंध में यदि धवन कुछ जवाब देते, तो बस यही कि सिख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती एक राजनीतिक निर्णय था, जिसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने निर्देश दिया था। इस संबंध में प्रधानमंत्री सुरक्षा के तात्कालिक अतिरिक्त उपायुक्त एचडी पिल्लई का बयान भी गौरतलब है। उनके अनुसार राजनीतिक निर्णय अरुण सिंह के माध्यम से राजीव गांधी तक पहुंचते थे। एक सूत्र का यह कहना है कि धवन ने पिल्लई की बात काटी नहीं थी।

यही नहीं, पिल्लई ने एसआईटी और ठक्कर आयोग के समक्ष यह भी बयान दिया था कि जब श्रीमती गांधी आपरेशन ब्ल्यू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर गयी थीं, तो उस दौरान बिना सिख सुरक्षाकर्मियों के उन्होंने मंदिर में जाने से इनकार कर दिया था। पिल्लई का कहना था कि उन्होंने उस समय श्रीमती गांधी की इस जिद का विरोध किया था, जिस पर अरुण सिंह और धवन ने उनसे कहा था कि राजनीतिक मामलों में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मजबूर होकर उन्होंने चार सिख सुरक्षाकर्मियों के साथ चार गैरसिख सुरक्षाकर्मियों की टोली बनायी थी, जिनको साथ लेकर श्रीमती गांधी स्वर्ण मंदिर गयी थीं। इन्हीं परस्पर विरोधी वक्तव्यों के चलते धवन को मिथ्या परीक्षण (लाइडिटेक्टर टेस्ट) से गुजरना पड़ा। यहां पर इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि जब धवन और जीआर गुप्ता दोनों के बयानों को छानबीन का आधार बनाया गया, तो सिर्फ धवन को ही मिथ्या परीक्षण से क्यों गुजारा गया? इस बात से यह सवाल उठता है कि क्या न्यायमूर्ति सिर्फ धवन को ही कठघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे?

> यह कैसे संभव है कि एसआईटी , जिसका नेतृत्व पुलिस अधिकारी के हाथ में था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमपी ठक्कर की छानबीन को गलत ठहराये?

ठक्कर का लक्ष्य : उपर्युक्त प्रक्रिया से जो बात उभर कर आती है, वह यही कि लगभग सभी धवन को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे थे तथा श्रीमती गांधी की हत्या की जिम्मेदारी से अपने को बचानेवाले अधिकारियों ने भी धवन को निशाना बना रखा था। इन्हीं बयानों को मद्देनजर रखते हुए न्यायमूर्ति ठक्कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की संदेह की सुई का रुख धवन की ओर ही ठहरता है। हालांकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कुछ और अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है, किंतु उनके खिलाफ कोई मजबूत आरोप नहीं लगाया। क्योंकि उनका ज्यादा ध्यान आरके धवन के चरित्र, व्यवहार, विश्वसनीयता तथा ईमानदारी को परख करने में लगा था तथा उसी पर उन्होंने ज्यादा समय खर्च किया। हालांकि न्यायमूर्ति ठक्कर की रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं कहा गया, जिससे आरके धवन को चार्जशीट दी जाती। न्यायमूर्ति ठक्कर ने रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से कहा, "अब तक जो सबूत सामने आये हैं, उनको मद्देनजर रखने पर धवन के इरादों का स्पष्ट पता नहीं चलता है। इसलिए बेहतर होगा कि धवन के इरादों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी रखा जाये और यदि प्रयास जारी रहा, तो निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल न होगा।" इन पंक्तियों के साथ ठक्कर आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट १९ नवंबर, १९८६ को पेश की तथा २७ फरवरी, १९८६ को अंतिम रिपोर्ट भी पेश कर दी। चूंकि अंतिम रिपोर्ट में भी निष्कर्ष स्पष्ट नहीं था, इसलिए ठक्कर रिपोर्ट के बाद चार्जशीट की नौबत नहीं आयी।

ठक्कर रिपोर्ट पेश होने के बाद उसके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए एसआईटी ने धवन के इरादों का पता लगाने के लिए तीन साल तक प्रयास किया। इस दौरान कई बार धवन से पूछताछ की गयी तथा गवाहों के सामने पेश किया गया जैसा कि सरकार का कहना है। तीन साल के कड़े परिश्रम और व्यापक छानबीन के बाद सरकार के अनुसार एसआईटी इस नतीजे पर पहुंची कि आरके धवन निर्दोष हैं। सरकार का कहना है कि एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार धवन का श्रीमती गांधी हत्याकांड से कोई संबंध नहीं था तथा वे किसी रूप में षड्यंत्र से नहीं जुड़े थे।

खबर यह भी है कि हाल में जब धवन की सेवाओं की जरूरत राजीव गांधी के लिए अपरिहार्य हो गयी, तो 'रा' के पूर्व अधिकारी जी सक्सेना तथा टीएन सेशान, जो उस समय रक्षा सचिव थे और अब कैबिनेट सचिव हैं, की दो सदस्यीय समिति गठित की गयी, जिसका काम आरके धवन पर लगाये गये आरोपों की असलियत जानना था। सक्सेना तथा सेशान छानबीन करके इस नतीजे पर पहुंचे कि धवन निर्दोष हैं। एसआईटी ने भी यही कहा कि उसे भी धवन के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक विपक्षी सांसद का आरोप है कि एसआईटी की रिपोर्ट सरकार के पक्ष में होते हुए भी उसे संसद में इसलिए नहीं पेश किया गया, क्योंकि एसआईटी अधिकारियों ने रिपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय के विरोध के बावजूद बैकडेट (पूर्व तिथि) में हस्ताक्षर किये। रक्षा मंत्रालय का विरोध सिर्फ इसलिए था, क्योंकि बूटा सिंह ने एक बयान में कह दिया था कि एसआईटी ने धवन को मार्च में निर्दोष घोषित किया, किंतु बाद में यह बयान जारी किया गया कि एसआईटी ने धवन को जनवरी में ही निर्दोष घोषित किया था। इन परस्पर विरोधी वक्तव्यों से यह जाहिर होता है कि सरकार अपनी गलती की लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। असल में होना यह चाहिए था कि धवन को वापस लाने से पूर्व ही धवन के निर्दोष होने का प्रमाण सार्वजनिक कर दिया जाता। खैर, सरकार से जो चूक हुई है, उसका खमियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आज विपक्ष जिस तरह से सवालात खड़े कर रहा है, वे कुछ और नहीं कांग्रेस की चूक का नतीजा हैं। लेकिन इन सब से कुछ साबित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक महत्वपूर्ण सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि यह कैसे संभव है कि एसआईटी , जिसका नेतृत्व पुलिस अधिकारी के हाथ में था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमपी ठक्कर की छानबीन को गलत ठहराये? इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा, जब एसआईटी द्वारा की गयी खोज की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जायेगा।

—माया टीम

पामेला की पगली यात्रा

—ममता कालिया

हाल ही दो भारतीय नाम दुनिया भर के अखबारों में हंगामा बरपा कर रहे हैं सलमान रुश्दी और पामेला बोर्डेस। दोनों अलग-अलग वजहों से चर्चित हुए हैं। रुश्दी ने इस्लामी देशों के मजहबी जज्बे को चोट पहुंचाई है, तो पामेला ने ब्रिटेन की सरकार हिला डालने का मसाला मुहैया किया है। लोगों के दिमाग में क्रिस्टीन कीलर की याद ताजा होने लगी है, बस किसी जान प्रोफ्यूमो पर उंगली ठहरने की देर है। जिन दो दर्जन नामों को पामेला के साथ जोड़ा जा रहा है, उनकी पुष्टि होने में समय है। अभी तो हालत यह है कि जिसके नाम की चर्चा उठती है, वही अपने कोट के बटन बंद करते हुए कहता है 'नाट मी, मैडम।'

इस सारे प्रकरण से यह आभास तो मिलता है कि पामेला में चर्चित होने और धन कमाने की बहुत हवस है। उसने मुंह खोलने की कीमत मांगी है, जबकि उसे पता नहीं वह मुह बंद रखने की भी कीमत मांग सकती थी। लेकिन तब वह गुमनामी के अंधेरे में जीती रहती। यह उसका मकसद नहीं था। हो सकता है वह खुश हो कि उसने दुनियाभर के अखबारों की सुर्खियां चुरा लीं। इतनी चर्चा तो वह विश्व-सुंदरी बन कर भी नहीं बटोर सकती थी।

सवाल इसका है कि क्या पामेला को वाकई शोहरत मिली है। सत्ताईस साल की उम्र इतनी कच्ची भी नहीं कि वह यह न समझ पाये कि बदनामी शोहरत के पिछवाड़े का नाम है। इस उम्र तक किसी भी इसान को यह तय कर लेना चाहिए कि वह अपने निशान कहां छोड़ना चाहता है, बर्तनों पर या बिस्तरों पर, हवा में या हवा के खिलाफ, परिवार में या बाजार में। 'बदनाम जो होंगे, तो क्या नाम न होगा' जैसी बचकानी ख्वाहिश सत्रह साल की उम्र में तो हो सकती है, सत्ताईस साल तक आते-आते वह बेहतर सोच में तब्दील हो जाती है। पामेला के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो इसकी वजह एक गहरी हताशा भी हो सकती है। संभवत: यह हताशा ही इस समूचे कांड का केंद्र-बिंदु है।

हम कल्पना करें एक ऐसी बच्ची की, जिसके होश संभालने से पहले पिता चल बसे हों, जिसकी उम्र का संवेदनशील हिस्सा होस्टल के निर्वैयक्तिक माहौल में गुजरा हो, जिसने एक-एक कर कई नौकरियों के लिए नाकाम कोशिश की हो, जो बेहद तल्ख तजुर्बों से गुजर कर भारत सुंदरी बनी हो और विश्व सुंदरी बनना चाहती रही हो। हर मुकाम पर कोई-न-कोई मायूसी और अकेलापन उसे एक गलत ढलान पर उतारते गये। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है कि आज पामेला को उन्हीं अखबारवालों से मुंह चुराना और भागना पड़ रहा है, कल जिनकी कलम से वह सरनाम होना चाहती थी। जिन महत्वपूर्ण लोगों के नाम उसकी जुबान से फिसले, उनके बारे में भी उसे बयान देना पड़ा कि उनसे उसका कोई यौन संबंध नहीं रहा।

आज जब पामेला अपनी मान-प्रतिष्ठा मटियामेट कर चुकी है, उसकी मां शकुंतला चौधरी का कहना है कि मेरी बेटी शुरू से उच्छृंखल थी और मैंने उसे बहुत पहले उसके हाल पर छोड़ दिया था। दरअसल पामेला की भटकन यहीं से शुरू होती है। ऐसा आभास मिलता है कि जीवन के हर नाजुक दौर में उसकी मां ने उसका साथ छोड़ दिया और वहीं से पामेला की अगली पगली यात्रा का सूत्रपात हुआ। आधुनिक रहन-सहन के अंतर्गत तथाकथित आधुनिकाएं परिवार का एक ऐसा पैटर्न बना लेती हैं, जिसमें बच्चों के संग-साथ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अकसर घर के कुत्ते-बिल्ली तो गोद में लेकर पाले जाते हैं और बच्चों को क्रेश और हास्टल में बड़ा किया जाता है। वहां उनके शरीर के विकास का तो पता लग जाता है, दिल-दिमाग के विकास और प्रभाव का पता तब लगता है, जब काफी देर हो चुकी होती है। बच्चे के ऊपर दस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव, भावात्मक थपेड़े, आक्रोशमय तनाव पडते हैं। बिना किसी मार्ग-दर्शन के इन सबसे बेदाग गुजर सकना हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं होता। माता-पिता बच्चे के जीवन में एक हद तक शाक एब्जार्वर का काम करते हैं, उसी तरह जैसे बड़े होने पर बच्चे अपने बूढ़े माता-पिता के लिए शाक एब्जार्वर का काम करते हैं। जहां भावनाओं का ऐसा स्वाभाविक आदान-प्रदान नहीं होता, वहां परिवार का कोई साफ नक्शा नहीं बनता। मुझे लगता है कि अब वह बिंदु आ पहुंचा है, जब पामेला अपनी मां से कहेगी, "तुम मुझे क्या त्यागोगी मां, मैं तुम्हें त्याग रही हूं। अपनाये जाने का भी एक समय होता है।"

इतनी चर्चा-कुचर्चा से पामेला के मन में अपने किये का क्या कोई पछतावा या अपराध-बोध पैदा हुआ है ? नगर के कुछ लोगों का खयाल है कि उसे अपराध-बोध है और इसीलिए वह विगत दिनों प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर एक प्रसिद्ध तंत्रस्वामी के शिविर में देखी गयी। उस पर अखबारों का ध्यान केंद्रित इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि एक तो तब तक खबर का भांडा फूटा नहीं था, दूसरे इस बात की पुष्टि नहीं हो पायी कि तंत्रस्वामी के साथ वह जो झिलमिली आंखों वाली युवती है, वह विश्व-सुंदरी है या भारत-सुंदरी। स्वयं तंत्रस्वामी ने चुप्पी साध कर इस रहस्य को बढ़ाया। पत्रकारों के सवालों का सामना संत और सुंदरी दोनों ने सार्थक मौन से किया। फिर महाकुंभ में प्रमुख संतों के शिविरों में एक नहीं अनेक देशी-विदेशी सुंदरियां आयी हुई थीं और सबका लेखा-जोखा रख पाना मुमकिन या जरूरी नहीं था।

बहरहाल थैचर सरकार के कंजर्वेटिव संसद सदस्य इस वक्त थर-थर कांप रहे हैं।कोई भी दिन के उजाले में जॉन प्रोफ्यूमो नहीं बनना चाहेगा। पूरे पामेला मामले की फिलहाल जांच चल रही है। असलियत सामने आने तक अटकलबाजियों का बाजार गर्म रहेगा, देशी-विदेशी अखबारों में पामेला के चित्र चकाचौंध मचाते रहेंगे, परस्पर-विरोधी वक्तव्य प्रकाश में आते रहेंगे और सत्ताईस साल की यह भटकी हुई लड़की एक शहर से दूसरे शहर भागती रहेगी। वह पायेगी कि चर्चा के कुटिल चक्र में पड़कर हालत यह हो गयी है कि उसके लिए कहीं बैठ कर चैन से एक प्याली चाय पीना भी हराम है। इस सारे प्रकरण में सबसे ज्यादा हानि उसी की है। बाकी लोग तो अपने-अपने दरवाजे बंद कर कह देंगे, "नो सेक्स प्लीज, वी आर ब्रिटिश।" ■

ऐसा आभास मिलता है कि जीवन के हर नाजुक दौर में उसकी मां ने उसका साथ छोड़ दिया और वहीं से पामेला की अगली पगली यात्रा का सूत्रपात हुआ।

क्या 'कूलर' खरीदना एक किलो चीनी खरीदने के समान है

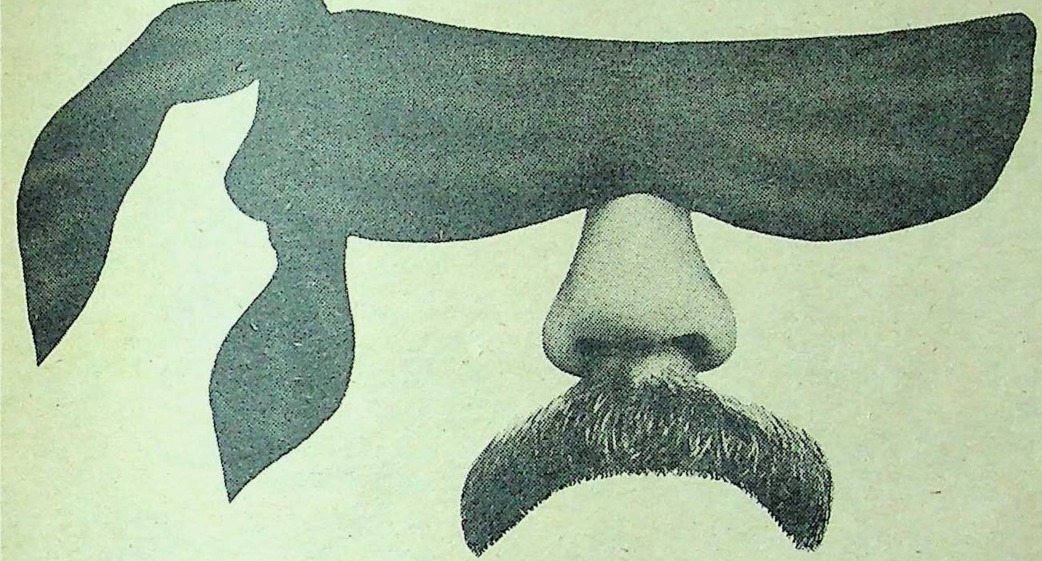

जरा सोचिए—आप डीलर के पास जाएं और "एक कूलर" की मांग करें, ठीक वैसे ही जैसे आप चीनी खरीदते हैं।

यह न जानते हुए कि शायद आप पाऐं एक ऐसा कूलर जिसमें घटिया व पुरानी तकनीक से बना कूलर पंखा व पम्प लगा हो। सिवाय इसके कि आप किसी एक नाम की मांग करें।

सिर्फ पोलर ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि पोलर कूलर पंखा और पम्प की मोटर पर चढ़ी बेक्टाल-2 की दोहरी परतें इसे जलने के खतरे से सुरक्षित रखती हैं और डाईनामिकली बेलेन्स ब्लेड अधिक हवा देते हैं।

इसलिए आप जब भी कूलर खरीदें तो चीनी की भाँति ना खरीदें। **विचार करें और** पोलर ही खरीदें क्योंकि पोलर ही 100% भरोसेमंद है।

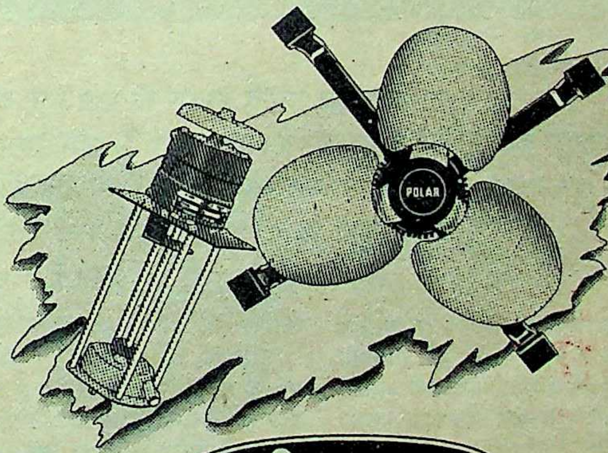

पोलर

कूलर पंखा & पम्प

सिर्फ सर्वश्रेष्ठ खरीदें - पोलर ही खरीदें

Pavitra/3291/1

इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट

एक और लाटरी घोटाला

अभी भी अधूरा: खेल प्रशाल

मप्र में चुरहट लाटरी प्रकरण की गरद अभी दबी भी नहीं थी कि एक और लाटरी कांड सुर्खियों में छा गया है। यह प्रकरण है, इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट द्वारा जारी की गयी लाटरी का। इस प्रकरण से एक संभ्रांत और प्रसिद्ध पत्रकार अभय छजलानी का नाम जुड़ा है जो 'नयी दुनिया' के स्वामी हैं। इस लाटरी प्रकरण के सभी पहलुओं की अफलातून पत्रकार वसंत पोतदार **ने अपने लहजे में खोजबीन की है। प्रस्तुत है, रिपोर्ट :**

लाटरी—एक चित्रमय शब्द है। इस शब्द के उच्चारण के साथ नोटों की गड्डियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। जिसकी लाटरी लगी, उसे मानो लक्ष्मी की 'किक' लग गयी। उसका नसीब खुल गया।

लेकिन हाल में मध्य प्रदेश में लाटरी के विजेता बदनसीब रहे हैं। एक से पंद्रह लाख रुपयों के इनाम घोषित होने पर भी उन्हें एक पाई नहीं मिली। विजेता ही नहीं, लाटरी संचालन से संबद्ध महाजनों का भी नसीब फूट रहा है। सभी जानते हैं कि लाटरी ने ही प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को सिंहासन से खींचकर उतारा है। उसी तरह भाग्यलक्ष्मी लाटरी भी दुर्भाग्य की अलक्ष्मी का विकराल रूप धारण कर चुकी है। अर्जुन सिंह समान दुर्गति क्या अभय छजलानी की भी हो सकती है? इंदौरवासी यह विचार करने में भी सिहर उठते हैं, उनका चिंतन मानो सहम जाता है।

सिर्फ इसलिये नहीं कि अभय छजलानी मालवे की कला और क्रीड़ा क्षेत्र के आधुनिक अग्रगामी हैं, इसलिये भी नहीं कि वे पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और इलना के अध्यक्ष हैं, बल्कि मालवांचल में लोग इसलिए स्तब्ध हैं कि अभय दैनिक 'नई दुनिया' के भागीदार हैं और सपादन कौशल के भी सुविज्ञ हैं।

'नई दुनिया की छाप: स्वतंत्रता वर्ष से मालवा 'नई दुनिया' से जुड़ा है। क्षेत्रीय भाषाओं में अन्य कुछ अखबार 'नई दुनिया' से छपाई और बिक्री में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन पाठकों के सोच पर स्थायी प्रभाव की बाबत शायद ही कोई 'नई दुनिया' का सानी हो। 'नई दुनिया' ने मालवांचल की मानसिकता बनायी है, मानो विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान होकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं कला, क्रीड़ा, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों मे श्रेष्ठ. कनिष्ठ कौन, इसके फैसले दिये हैं और उन्हें लोकमान्यता मिली है। सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन, श्रेष्ठ खिलाड़ी, चिकित्सक, शिक्षाविद कौन इसका निर्णय 'नई दुनिया' देता आया है और वैसा ही ढलता रहा है जनमत।

पृष्ठ भूमि: ऐसे दैनिक के एक मालिक के खिलाफ इंदौर के कुछ अखबार और विपक्षी दल के नेताओं के हठात् हल्ला बोल देने से जनता असमंजस में पड़ गयी है। टेबल टेनिस के क्षेत्र में इंदौर का नाम भारतीय खेल-कूद के नक्शे पर एक मानचिन्ह के रूप में लाने में अभय के कई वर्षों के परिश्रम का योगदान महत्वपूर्ण है। इंदौर के सुरेश गावड़े भारतीय टेटे (टेबल टेनिस) फेडरेशन के वर्तमान सचिव हैं। कु० रिंकू गुप्ता इस वर्ष भारतीय स्तर पर अव्वल स्थान पानेवाली इंदौर की पहली महिला खिलाड़ी

है। अभय ने टेटे के लिए एक खेल प्रशाल (स्टेडियम) का निर्माण कार्य जब शुरू किया, तब मप्र सरकार ने उन्हें लाटरी के तीन ड्रा निकालने की अनुमति दी थी। वह लाटरी-कांड ही आज के क्षेत्रीय वातावरण की बेसुरी गूंज है। अभय के खिलाफ जो कुछ लिखा-बोला जा रहा है, उसके उत्तर उनके सिवा कौन दे सकता है? मैं उनसे मिला। उनके साथ सुरेश गावड़े भी थे, जो शालेय जीवन से ही मेरे मित्र हैं। हम तीनों के अलावा एक महिला भी उपस्थित थी। वह बहुत कुरूप स्त्री मानी जाती है। नाम है 'मिस वस्तुस्थिति'। बीच-बीच में वह भी बोली। हम चारों द्वारा खेला हुआ संवादनाट्य इस प्रकार है:

मैं: *खेल-प्रशाल की जमीन कैसे मिली इसकी पृष्ठभूमि बतायेंगे?*

अभय: *यशवंत क्लब के पीछे की २०-२१ एकड़ जमीन खेल के वास्ते देने का निर्णय प्रकाश चंद्र सेठी जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लिया था। टेबल टेनिस के लिये हमें जमीन चाहिए ही थी। मैंने क्रिकेट, लॉन टेनिस और बास्केट बाल संगठनों को भी अर्जी देने को कहा। अर्जी पर मेरे साथ उन्होंने भी दस्तखत किये। उसके बाद कई वर्षों तक मैं अकेला सरकार के पीछे पड़ा रहा। जो नया मुख्यमंत्री आता उससे मैं जमीन की अपनी मांग दोहराता। आखिर १९७५ में मुझे सफलता मिली। अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को जब मैंने जाकर बताया कि पटवारी, तहसीलदार जमीन की नप्ती करने आये हैं, अपनी-अपनी जमीन ले लो, तब उन्हें भूमि प्राप्त होने का पता चला।*

मैं: *मतलब आपके प्रयासों से ही अन्य तीन खेलों को जमीन मिली?*

अभय: *निस्संदेह।*

मैं: *टेबल टेनिस के लिए कितनी जमीन मिली?*

अभय: *तीन एकड़ से कुछ अधिक।*

मैं: *किस दर से?*

अभय: *हम सभी को निःशुल्क मिली है भूमि। एक आदेश द्वारा हमें सूचित किया गया कि यह भूमि हमको खेलों के वास्ते देने का सरकार ने निर्णय लिया है। बस। किराये का कोई उल्लेख नहीं है आदेश में।*

वस्तुस्थिति: २ मई, १९७७ को नजूल विभाग ने टेटे जिला संगठन सचिव सुरेश गावड़े को जमीन का कब्जा दिया, यह पत्र क्रमांक रापक ८ अ-२०/२८ उपलब्ध है। इसके सात वर्ष बाद अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में एक नया आदेश निकाला गया, जो इन चारों संगठनों तक पहुंचा ही नहीं। भोपाल से निकला यह आदेश कहां गायब हुआ यह अभी तक रहस्य है। भोपाल से जिलाधीश, इंदौर के नाम दिनांक १८.६.१९८४ को क्र० ६-१७२/आठ (९) १७६ के तहत निकले आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक संगठन से बगैर प्रत्याजी तथा एक रुपए प्रति एकड़ वार्षिक भू-भाटक की दर से स्थायी पट्टे पर सामान्य शर्तों के साथ निम्न शर्तों पर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आदेश की दो शर्तें महत्व रखती हैं। पहली यह कि ५ वर्षों में पूरा उपयोग न करने पर शासन खेल-संगठनों से जमीन वापस ले लेगा तथा समुचित कारण बताने पर समावधि बढ़ाई जा सकेगी। दूसरी शर्त है कि स्टेडियम की गैलरी के नीचे केवल क्रीड़ा-सामग्री बेचने की दुकानें और संगठनों के कार्यालय बनाये जायें और उनसे मिलनेवाले किराये से स्टेडियम का रखरखाव किया जाये।

यह आदेश गायब हो गया। इसे अमल में लाया जाता, तो इंदौर में चार स्टेडियम बन जाते। खेलों का सामान बेचनेवाली दुकानें बढ़ जातीं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालय न होते।

मैं: *खेल-प्रशाल की आय के स्रोत बतायेंगे?*

अभय: *अंदाजन बता सकूंगा। एकाध लाख कम या ज्यादा हो सकते हैं। मप्र शासन से हमें अब तक सोलह (१६) लाख मिले हैं। केंद्र सरकार से बीस (२०) लाख। लाटरी की रायल्टी से बत्तीस (३२) लाख। लता मंगेशकर रजनी से छह (६) लाख से कुछ अधिक। १९८४ में खेल-प्रशाल में हमने दो प्रतिष्ठानों को किराये पर जगह दी। जून माह में रैनबक्सी कंपनी को प्रतिमाह २१,९०० रुपए किराये पर और एक अगस्त १९८४ से इंडियन एअरलाइंस को १२,४५० रुपए प्रतिमाह पर। ये सोलह-सत्रह (१६-१७) लाख हुए होंगे। प्रतिष्ठित व्यवसायी, गणमान्य नागरिक और आम आदमी ने ११ रुपए प्रतिमाह से एकमुश्त एक लाख तक जो दान भवन निर्माण के लिये दिया, वह है करीब २५ लाख। लगभग एक करोड़ रुपए हमें अब तक प्राप्त हुआ है।*

वस्तुस्थिति: स्नेहदान से प्राप्त रकम २५ लाख से चौगुनी होने का अनुमान है। इंदौर धनाढ्य शहर है और प्रायः सभी दिग्गज उद्योगपति, सरकारी अफसर, डाक्टर, वकील, अध्यापक, बैंक मैनेजर, कवि-लेखक, कलाकार, खिलाड़ी आदि 'नई दुनिया' से जुडे हैं।

मैं: *और निर्माण में कितना खर्च हुआ अब तक?*

अभय: *एक करोड़ बीस लाख। यह मैं अनुमानतः बता रहा हूं।*

मैं: *बीस लाख का घाटा कैसे पूरा किया आपने?*

अभय: *कुछ मदद मेरे मित्रों ने की।*

सुरेश गावड़े: *करीब दो लाख टेटे खिलाड़ियों ने दिया। ट्राफी के बजाय हम उन्हें नकद पुरस्कार देने लगे। यह कहकर कि पुरस्कार की राशि अभी हम भवन निर्माण में लगा रहे हैं। प्रशाल पूरा होने पर आपको इनाम की रकम लौटा दी जायेगी। वे सब मान गये।*

अभय: *अपने खिलाड़ियों में मैं इस भावना का निर्माण करना चाहता हूं कि वे इस वस्तु को अपना समझें।*

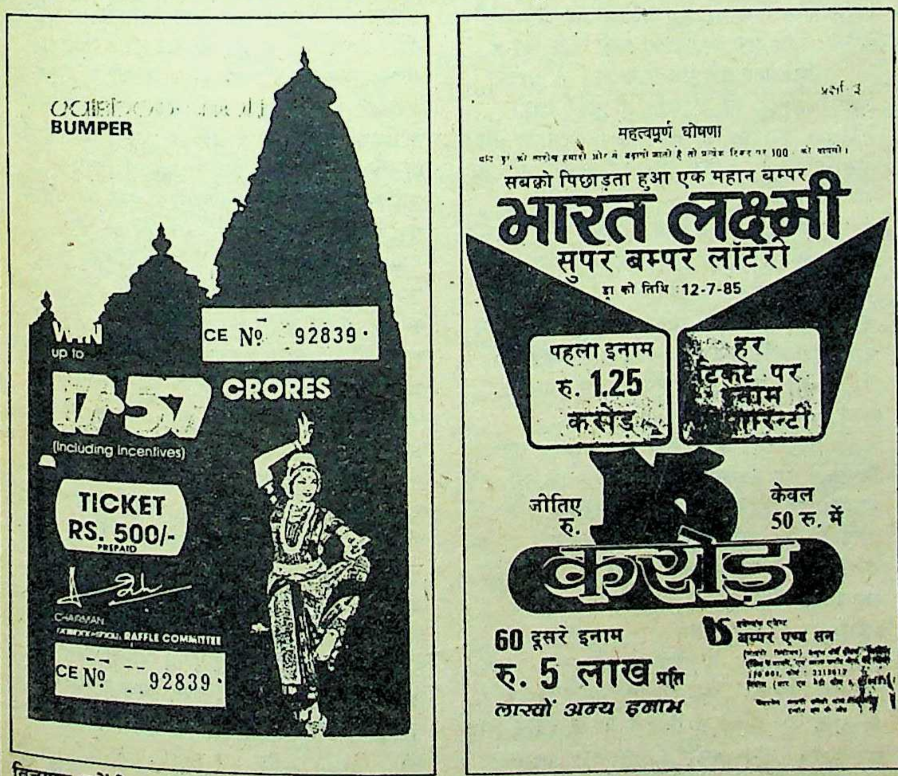

BUMPER

WIN up to 17.57 CRORES (Including Incentives)

CE №. 92839

TICKET RS. 500/- PREPAID

CHAIRMAN RAFFLE COMMITTEE

CE №. 92839

महत्वपूर्ण घोषणा

सबको पिछाड़ता हुआ एक महान बम्पर

भारत लक्ष्मी सुपर बम्पर लॉटरी

ड्रा की तिथि : 12-7-85

पहला इनाम रु. 1.25 करोड़

हर टिकट पर इनाम गारन्टी

जीतिए रु. 15 करोड़ केवल 50 रु. में

60 दूसरे इनाम रु. 5 लाख प्रति

लाखों अन्य इनाम

बम्पर एण्ड सन

विज्ञापन क्यों? : ५०० रुपए का टिकट (बायें) व ५० रुपए का टिकट

ट्रस्ट को चूना यों लगा

चुरहट लाटरी कांड पर लिखे अग्रलेख में दिल्ली के नवभारत टाइम्स (२३-९-१९८८) ने लाटरी संबंधी उपमहालेखागार की शासकीय रिपोर्ट दी है। संपादक के मूल शब्द इस प्रकार हैं:

'मध्य प्रदेश में १९८०-८५ के दौरान ७३ व्यक्तियों और संस्थाओं को लाटरियां चलाने का लाइसेंस दिया गया। इनमें से २७ न, न तो छपे और बिके टिकटों का और न ही पूरे पैसों के आय-व्यय का कोई हिसाब-किताब दिया। और जिन ४६ का हिसाब-किताब आया उसमें टिकटों की बिक्री से कुल ३५८ लाक २७ हजार रुपया जुटाया गया, जिस पर २५ प्रतिशत के हिसाब से ८९ लाख ५९ हजार रुपया टैक्स लगता था, जबकि ७ लाख १६ हजार रुपया टैक्स आंका गया और सरकारी कोष को खालिस ८२ लाख ४३ हजार रुपए का चूना लगा।

इंटेट ट्रस्ट को टैक्स से मुक्त किया गया था। फिर भी खेल प्रशाल निर्माण में लगनेवाला पैसा ट्रस्ट दो ड्रा से खड़ा नहीं कर सका। प्रशाल अधूरा है, इनाम के लाखों रुपए का बोझ ट्रस्ट पर है, इसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। मुकदमेबाजी अलग चल रही है। जिन लोगों पर आरोप हैं, उन्हें क्रमवार देखते हैं:

१- अय्यर एण्ड संस ने ट्रस्ट को पंजाब नेशनल बैंक, लाजपतनगर शाखा, नयी दिल्ली के नाम का ३५ लाख रु० का झूठा गारंटी बांड दिया। बैंक ने लाजपतनगर पुलिस में शिकायत दर्ज की। २० जुलाई, १९८५ को लिखे पत्र में बैंक ने लिखा, 'अय्यर एण्ड संस' ने इंटेटे ट्रस्ट के साथ मिलकर हमें धोखा देने की कोशिश की।'

२- 'हम षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, उल्टे एजेंट ने २९९८३३ टिकट विक्रय कर जनता से १ करोड़, ४९ लाख, ९१ हजार ६५० रुपए प्राप्त किये।' ऐसी रिपोर्ट लाटरी कमेटी के चेयरमैन अरुण दुबे ने इंदौर के छत्रीपुरा थाने में १०-१०-१९८५ को की। दुबे ने यह भी लिखा कि एजेंट हमें १० लाख रु० सुनिश्चित लाभ देने वाले थे, उसमें से सिर्फ ४ लाख रु० प्राप्त हुए हैं।

३-डेढ़ करोड़ रु० के टिकट बिकते हैं और विजेताओं से लेकर ट्रस्ट तक एजेंट सबको धोखा देते हैं। यह सब पता लगने पर भी विजेताओं के पत्र मिलने पर ट्रस्ट उन्हें एजेंट से पत्र व्यवहार करने को लिखते हैं। यह ट्रस्ट द्वारा जनता के साथ किया हुआ धोखा नहीं है क्या?

४- अब मध्य प्रदेश का लाटरी एक्ट देखें। सेक्शन ६ कहता है (अ) टिकट वास्ते कागज और छपाई-खर्च छोड़कर सारी राशि इनामों वास्ते रखी जाये, (ब) विज्ञापन न किये जायें। एक्ट का ११ क्रम का नियम कहता है कि लाटरी खुलने के ७ दिनों के भीतर शासन को पूरा हिसाब देना ही चाहिए।

एक्ट स्पष्ट शब्दों में कहता है कि एजेंट की नियुक्ति गैरकानूनी है और अगर एजेंट से अनुबंध किया जाता है, तो भारतीय करार एक्ट सेक्शन २३ के तहत उसे शून्य माना जाये।

ट्रस्ट ने एजेंट रखा। अभय ने कहा कि उन्होंने जिन एजेंसीज से करार किया वे मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों की लाटरी निकालने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा मान्य थे, विश्वसनीय थे। लेकिन राज्य सरकारों ने १५ से २० प्रतिशत कमीशन पर उन्हें रखा था, बस यही फर्क है। इंटेटे ट्रस्ट ने चंद्रा एजेंसीज तथा अय्यर एण्ड संस को कमीशन पर नहीं रखा था। इसे हम नहीं भूलें। स्टेशनरी और छपाई के अलावा किसी भी प्रकार का खर्च न दिया जाये, यह कानून होने के बावजूद ट्रस्ट के एजेंटों की बैलंस शीठ दिखाती है कि विज्ञापन वाहन और पेट्रोल आदि पर भी लाखों खर्च किये गये हैं।

विज्ञापन पर सर्वाधिक खर्च है, जबकि एक्ट विज्ञापन की अनुमति ही नहीं देता। (देखिए विज्ञापन का चित्र।) ७ दिन के भीतर हिसाब देने का नियम तो ट्रस्ट ने ताक पर ही रख दिया है।

सरकारी लाटरी का टिकट १ रुपए में और प्राइवेट लाटरी का टिकट २ रुपए में बेचने का नियम है। ट्रस्ट के एजेंट अय्यर ने भारत लक्ष्मी लाटरी टिकट का मूल्य रखा था ५० रुपए और चंद्रा एजेंसीज के वैभवशाली लाटरी का टिकट रखा गया था पूरे ५०० रुपए।

५-चुरहट लाटरी में अदालत का स्पष्ट निर्णय है कि विजेताओं को इनाम देने की पूरी जिम्मेदारी, जिसे लाटरी का लाइसेंस मिला है, उसी की है। वही नियम समस्त लाटरी जगत वास्ते (मप्र के) लागू है। फिर भी इंटेटे ट्रस्ट सारा दोष ऐसे एजेंटों के मत्थे जड़ रहा है जिनका कोई पता ठिकाना ही नहीं है।

६-मोतीलाल वोरा सरकार की मूर्खता भी गौर करने लायक है। एडमिरल मिश्रा को ५ लाक का इनाम न मिलने पर वे इंदौर आये थे। इंदौर जिला अपराध अनुसंधान शाखा ने उनकी शिकायत सही पायी और मामला जूनी इंदौर थाने के पास भेजा। तफ्तीश किसके खिलाफ करनी थी? ट्रस्ट के खिलाफ, क्योंकि एजेंट के खिलाफ करनी होती, तो मामला दिल्ली पुलिस के सुपुर्द किया जाता। ट्रस्ट न 'नई दुनिया' के माध्यम से इंदौर में समांतर सरकार चलाता है। जूनी इंदौर थाना प्रभारी से तफ्तीश न करने को कहा गया। मामला चौकी के मालखांने में रख दिया गया। तब प्रभारी थे श्रीवास्तव। उनकी जगह पर जुलाई १९८८ में जगतनारायण शर्मा आये। मालखाने में शर्मा को एडमिरल मिश्रा की डायरी और ५ लाख का टिकट दिखा। उनके पूछने पर बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से वह दस्तावेज सुरक्षित रखा गया है और अनुसंधान न करने के आदेश दिये गये हैं। २८ से ३० सितंबर के बीच एडिशनल एसपी अशोक जैन थाने का मुआयना करने आये। उन्होंने मिश्रा के केस का खात्मा करने का आदेश दिया।

जनवरी १९८९ के अंत में मुख्यमंत्री बदले। खात्मा करने के जुर्म में १५-२-८९ को शर्मा का निलंबन और उनके सीएसपी बदनसिंह यादव का दबादला किया गया। आननफानन निर्णय लेकर स्वयं को स्मार्ट दिखाना चाहती थी वोरा सरकार। चुरहट के बाद इंटेटे ट्रस्ट का घपला खतम करने का दावा जनता से करने का सरकार का वह स्टंट था। लेकिन प्रभारी शर्मा ने बयान दिया कि एडिशनल एसपी अशोक जैन के दबाव में आकर उन्होंने खात्मा किया। उन्होंने कहा, "अभय छजलानी मुझ पर दबाव ला रहे हैं, किस्सा खतम करो।' तब वोरा सरकार को पता चला कि 'नई दुनिया' के उज्जैन के एजेंट अवंतिलाल जैन के रिश्तेदार है अशोक जैन। गलत व्यक्ति हैं अशोक जैन, न कि शर्मा और बदनसिंह यादव। यादव ने भी २३-२-८९ को लिखित बयान दिया कि अशोक जैन नामक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को मैंने अनुमोदित किया था। यह सब सत्य कथा समझते ही वोरा सरकार ने जगतनारायण शर्मा को निलंबन ३ मार्च, १९८९ को रद्द करके उन्हें राजेंद्र नगर का थाना प्रभारी बना दिया।

लेकिन अशोक जैन और उनके संरक्षक अभय छजलानी के खिलाफ मोतीलालजी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ट्रस्ट के लाटरी संबंधित अगणित घपलों के सरकारी दस्तावेज उनके पास होने पर भी मोतीलाल वोरा मौन क्यों हैं? डरपोक व्यक्ति की अहिंसा है क्या यह?

—व०पो०

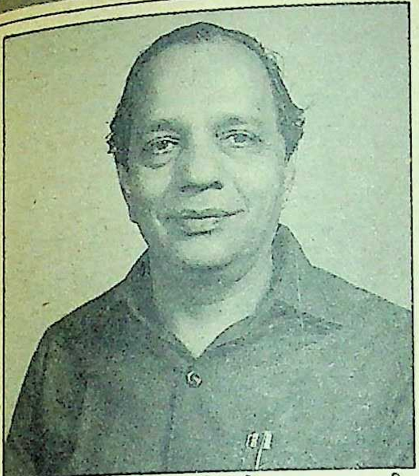

गलती हो सकती है, गड़बड़ी नहीं : अभय छजलानी

मैं : *अभी कितना निर्माण कार्य बाकी है और उसमें कितना धन आवश्यक है ?*

अभय : *निर्माण दो भागों में बंटा है। पहला भाग है, प्रशाल प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त हो। अभी हमें छत बनाना है। ४४ हजार वर्गफीट पर जीआई शीट की छत बनेगी। इसमें ३५ लाख खर्च रु० के का अनुमान है। दूसरे भाग में हमारे मास्टर प्लान के अनुसार एक अभ्यास गृह और एक तरण-लालकर बनाना है। हम प्रशाल में विराट सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहते हैं। उसके लिये चाहिए उत्तम ध्वनि व्यवस्था और एअर-कूलिंग। यह सब इसलिये कि वास्तु (इमारत) के माध्यम से खास और आम जनता का खेलों के प्रति आकर्षण बढ़े। उसमें ३०-३५ लाख लगेंगे। शहर इजाजत देगा, तो हम उसे भी बनायेंगे।*

मैं : *अब हम 'लाटरी' पर आते हैं। मोहनसिंह शाह ने मुझे बताया कि आपने लाटरी एक्ट का कानूनन पालन नहीं किया है।*

अभय : *जो मोहनसिंह शाह बता रहे हैं, वैसे कानून की जानकारी हमें नहीं है। हमें सरकार ने जिन शर्तों का पालन करने के आदेश दिये थे, वे पूरे करने के बाद ही हमने लाटरी का टिकट फ्लोट किया था।*

मैं : *अच्छा, यह बताइये कि चुरहट लाटरी के एजेंट ए. एण्ड ए ही क्या अय्यर एण्ड संस हैं ?*

अभय : *जी नहीं। अय्यर एण्ड कंपनी उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम लाटरी का संचालन कर रही थी। वैसे, वसंतजी एक विश्वसनीय बात बताता हूं। एक विजेता को छोड़कर अय्यर एण्ड कंपनी से इनाम पाने का कोई दावेदार आज की तारीख में नहीं है। एजेंट का कहना है कि उस एकमात्र शेष विजेता का अता-पता नहीं मिल रहा है। एजेंट उसकी तलाश कर रहा है और मिलने पर उसे संतुष्ट कर देगा।*

वस्तुस्थिति : अय्यर एण्ड कंपनी के साथ विजेताओं के पत्र-व्यवहार के लिए, पढ़िये लेख 'जिनके नसीब फूटे'।

मैं : *लाटरी के तीन ड्रा दो वैभवशाली और एक भारतलक्ष्मी से अब तक आपको ३२ लाख रायल्टी मिली। अभी कितना पैसा बकाया है ?*

अभय : *अय्यर एण्ड कंपनी से हमारा अनुबंध था कि टिकट बिके ना बिके, वे हमें दस (१०) लाख की सुनिश्चित रकम देंगे। टिकट बिक्री बढ़ने के साथ रायल्टी की रकम भी बढ़ती जायेगी। उस दस में से हमें करीब साढ़े आठ लाख ही मिले हैं। हमें एजेंट से अभी अनुमानतः कुल २३-२४ लाख लेना बाकी है। सही आंकड़े मैं नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें हमने अदालत में पेश किया है। अगर लाटरी से यह बकाया पैसा आ जाता है, तो मैं प्रशाल निर्माण की पहली पायदान पूरी कर लूंगा।*

मैं : *आपको ऐसा नहीं लगता कि विजेताओं को धोखा दिया गया है ?*

अभय : *मैं यह तो नहीं मानता कि धोखा दिया गया है। इतना ही कहूंगा कि एजेंसी ने ठीक समय पर अपने कमिटमेंट का पालन नहीं किया। वैसे वह एजेंट तब मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा राज्य की लाटरियों का भी संचालन कर रहा था। आंध्र के एक अस्पताल की सहायतार्थ उसने दो करोड़ से भी अधिक धन संग्रहीत किया था। एनटीआर ने उसे सम्मानित किया था, जिसका फोटो खुद मैंने देखा है।*

मैं : *क्या नाम है एजेंट का ?*

अभय : *अ...? खन्ना।*

मैं : *कौन खन्ना ? उनका पता ?*

अभय : *के खन्ना। वे दिल्ली में रहते थे। उनका वर्तमान पता मेरे पास नहीं है। मप्र की रेडक्रास की लाटरी खन्नाजी कर चुके थे। तभी मैंने उनसे संपर्क किया। किसी अज्ञात व्यक्ति से मैंने करार नहीं किया था। बस, दुर्भाग्य यह है कि हवन करते हुए उंगली जल गयी। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तब यह सोचता हूं कि मुझे क्या पड़ी थी ये काम करने की ? मैं मजे में था। मेरा अखबार अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरी तमन्ना है कि हमारा शहर अखिल भारतीय नक्शे पर आये। हमने खेल-कूद में काम किया, राजनीति नहीं खेली। हमारा एक भी पदाधिकारी राजनीति से संबद्ध नहीं है। हमने 'आउट आफ द वे' जाकर राजनीतिज्ञों से मदद भी नहीं ली है। यह हमारी टेटे के काम की २० वर्षों की तपस्या है, जो आज फलीभूत दिखाई दे रही है। अच्छी गतिविधियों से शहर की संस्कृति परिवर्तित होती है, यह मेरी मान्यता है। खेल प्रशाल पूरा होने पर वह भारत भर की पहली वास्तु होगी, जो जनता के पैसों से बनी होगी। कोचीन में एक वास्तु सरकारी मदद से बन रही है, जमशेदपुर में भी एक बन रही है, टाटा की मदद से। जनता को इनवाल्व करके खेल प्रशाल बनाने की भारत भर में यह पहली कोशिश है।*

आलोचना तो होती ही है : सुरेश गावड़े

वस्तुस्थिति : अगर यह जनता मंच का निर्माण है, तो अनुदान में केंद्र से मिले २० लाख और मप्र शासन के १६ लाख लौटाने की जिम्मेदारी भी जनता को ही उठानी होगी।

मैं : *प्रशाल निर्माण में अड़ंगा कौन लगा रहा है ?*

अभय : *ईर्ष्या करनेवाले कम नहीं हैं। ये वे लोग हैं, जिन्हें शहर में अवैधानिक धंधे करके पैसा कमाने में रुचि है। मैं और मेरे सारे साथी विरोधियों के निराधार प्रचार से बिलकुल अविचलित हैं...*

वस्तुस्थिति : सतही तौर पर अभय का कथन सही है। सुरेश गावड़े का कहना है, "लाटरी के मामले में मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं। फिर भी सारी जिम्मेदारी और बुराई लेने को मैं तैयार हूं। जनकार्य शुरू करने पर विरोध की धूल उड़ती ही है। उसे हजम करके मैं अपने साथियों पर लगे इलजामों का भागीदार बना रहूंगा। इंदौर के जो अखबार खेल प्रशाल पर आज कीचड़ उछाल रहे हैं, वे कल प्रशाल निर्माण पूरा होने पर चुप बैठ जायेंगे। खेल प्रशाल बना, तो भारतीय टेटे फेडरेशन का सचिव होने के नाते उसका सर्वाधिक फायदा मैं ही उठा पाऊंगा। जो आलोचना हो रही है, उसका मुझ पर कोई असर नहीं।" इंदौर टेटे ट्रस्ट के दो विश्वस्त श्री रमेश कहेती और डा० भरत छापरवाल भी सुरेश गावड़े की सी ही निर्भय भाषा बोलते हैं।

अभय : *संस्था को चलाने के लिये कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली, हिसाब बराबर हो। दूसरी, जिन सरकारी कार्यालयों को हिसाब देना पड़ता है, उन्हें समय पर दिया जाये और अगर कोई गलती हुई है, तो बिना लागलपेट के उसे स्वीकार कर लिया जाये। ३१ मार्च, १९८८ तक का हिसाब मैंने आयकर विभाग को बराबर दिया है। विभाग को दिये गये हिसाब में गलती हो सकती है, गड़बड़ी नहीं। विभाग द्वारा १९८६-८७ का दिया असेसमेंट आदेश मेरे पास है।*

मैं : *तब वह आप विरोधियों को क्यों नहीं दिखाते ?*

इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट

जिनके नसीब फूटे

इस निर्धन देश में एक रुपए की आमदनी को तरसने वाली प्रजा ही असंख्य है, ऐसे में लाखों रुपए की लाटरी लगना भाग्यशिखर पर विराजमान होना है। जिस दिन निर्णय घोषित हुआ विजेता किस कदर खुश हुए होंगे? धड़ल्ले से पार्टियां की होंगी। उनके परिवारों ने क्या-क्या सुनहरे सपने बुने होंगे, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि सब सपने शेखचिल्ली साबित हुए होंगे।

टेबल टेनिस के दोहरे मुकाबले में गेंद तड़ातड़ उड़ती रहती है। चार खिलाड़ी उसे धुनकते रहते हैं। कई दुर्भाग्यशाली लोगों की हालत उस गेंद-सी हुई है। एजेंसी, ट्रस्ट मालिक, अदालत और पुलिसथाना, इन चारों के पास टप्पे खा रहे हैं बेचारे। अंपायर है मप्र सरकार। निर्णय देने के बजाय वह साध बैठी है शिखंडी-चुप्पी।

एडमिरल एसएन मिश्रा: भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त एडमिरल मिश्रा ११ न्यू रोड, अलीपुर, कलकत्ता—७०००२७ के निवासी हैं।

१२ जुलाई, १९८५ को इंदौर में खोले गये भारतलक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी का टिकट नंबर एए—१३६८३३ मिश्रा ने खरीदा था। उनके नंबर पर द्वितीय पुरस्कार घोषित हुआ। इनाम राशि थी पूरे पांच लाख रुपए।

ठीक एक माह इंतजार करके मिश्रा ने १२ अगस्त, १९८५ को अय्यर एंड संस को तार किया। जवाब न आने पर आठ दिन बाद २० अगस्त को पत्र लिखकर मूल टिकट की छायाप्रति, शपथ पत्र, पारपत्र के आकार का कलकत्ता मेट्रोपोलिटन मैजिस्टेट द्वारा सत्यापित्त छायाचित्र आदि भेजा। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। मिश्रा रहे हैं नौसेना के एडमिरल। वे चुप नहीं बैठे। कलकत्ते से दिल्ली, भोपाल और इंदौर के चक्कर लगाने लगे। कब तक? तीन वर्षों तक। जब कोई नतीजा नहीं निकला तब इंदौर जिला। अपराध अनुसंधान शाखा के यहां मिश्रा ने दस्तक दी। शाखा ने जांच की। मिश्रा का दावा सही पाया और मामला जूनी इंदौर थाने को सौंपा। पुलिस ने ट्रस्ट के अध्यक्ष के खिलाफ धारा ४२० में ७ फरवरी, १९८८ को दिन के एक बजे रोजनामचा क्रमांक ८०/८८ के तहत प्रकरण दायर किया।

लेकिन प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता दल के नेताद्वय मोहन सिंह शाह और संतोष गावड़े ने १४ फरवरी, १९८९ को

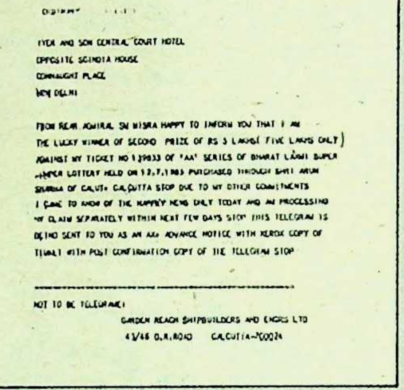

IYER AND SON CENTRAL COURT HOTEL
OPPOSITE SCINDIA HOUSE
CONNAUGHT PLACE
NEW DELHI

FROM REAR ADMIRAL SN MISRA HAPPY TO INFORM YOU THAT I AM
THE LUCKY WINNER OF SECOND PRIZE OF RS 5 LAKHS(FIVE LAKHS ONLY)
AGAINST MY TICKET NO 139833 OF 'AA' SERIES OF BHARAT LAXMI SUPER
BUMPER LOTTERY HELD ON 12.7.1985 PURCHASED THROUGH SHRI ARUN
SHARMA OF CALUT CALCUTTA STOP DUE TO MY OTHER COMMITMENTS
I CAME TO KNOW OF THE HAPPY NEWS ONLY TODAY AND AM PROCESSING
MY CLAIM SEPARATELY WITHIN NEXT FEW DAYS STOP THIS TELEGRAM IS
BEING SENT TO YOU AS AN AA ADVANCE NOTICE WITH XEROX COPY OF
TICKET WITH POST CONFIRMATION COPY OF THE TELEGRAM STOP

NOT TO BE TELEGRAPHED

GARDEN REACH SHIPBUILDERS AND ENGRS LTD
43/46 G.R.ROAD CALCUTTA-700024

इनाम की गुहार: मिश्रा का तार

इंदौर में पत्रकार परिषद में इसका कारण यह बताया है कि मामला दर्ज होने के चार दिन बाद ही अर्जुन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उक्त पत्रकार परिषद के तत्काल बाद आये नये मुख्यमंत्री वोरा ने जूनी इंदौर थाना प्रभारी जगतनारायण शर्मा को ढीलपोल के कारण निलंबित कर दिया, मगर मिश्रा का इनाम आज भी अधर में है।

लोकेन्द्र नाथ साइकिया: डिब्रूगढ़ के आय-कर कार्यालय में कार्यरत लोकेंद्रनाथ साइकिया के कुल सात दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं। १७ जुलाई से २६ सितंबर १९८५ तक असम में बैठकर दिल्ली और इंदौर पत्र भेजकर परेशान हुए साइकिया के दस्तावेजों से साफ जाहिर होता है कि अय्यर एंड संस तथा इंदौर टेटे ट्रस्ट की इनाम देने की नीयत ही नहीं थी। तर्क को यहां तक खींचा जा सकता है कि इनामों की घोषणा करने तक ही उक्त दो संस्थाओं की कार्यसीमा थी। संक्षेप में दस्तावेज इस प्रकार हैं:

१—साइकिया का ट्रस्ट के चेयरमैन को लिखा १७ जुलाई, १९८५ का पत्र: '१०.५.८५ को खुलनेवाली भारतलक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी आखिर १२.७.८५ को खुली और मुझे अपने टिकट क्रमांक जीजी १३४३७५ पर एक लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार मिला है। मैं टिकट की छायाप्रति अपने तीन छायाचित्र और इनाम प्राप्त हुआ इसकी भी अग्रिम रसीद स्टेट बैंक आफ इंडिया की डिब्रूगढ़ शाखा के द्वारा भेज रहा हूं। कृपया आयकर काटकर, उसके सर्टिफिकेट के साथ मेरी रकम बैंक में जमा करवायें।'

२—डिब्रूगढ़ के अतिरिक्त कमिनश्नर द्वारा अटेस्टेड साइकिया की टिकट लगी रसीद कि बैंक के माध्यम से उन्हें एक लाख रुपए प्राप्त हुए।

३—अय्यर एंड संस (लाटरी डिवीजन) के एक भागीदार आरएस सेठी का १०.६.८५ को साइकिया को लिखा एक पत्र: 'टेटे ट्रस्ट ने हमें सूचित किया है। आपके टिकट की हम अपने छापखाने के मालिक से और आवश्यकता पड़ने पर मुद्रण-विशेषज्ञों से जांच करायेंगे। जांच से आपके टिकट की सत्यता सिद्ध हुई, तो आय-कर बोनस आदि काटकर टेटे ट्रस्ट, इंदौर आपको राशि देगा।'

४—साइकिया का ५.११.८५ को टेटे ट्रस्ट के अध्यक्ष को लिखा पत्र, जिसकी प्रतियां अय्यर एंड संस के सेठी और स्टेट बैंक आफ इंडिया की इंदौर और डिब्रूगढ़ शाखाओं को भेजी गयीं। पत्र-व्यवहार से पस्त दूर असम में बैठे साइकिया लिखते हैं: 'सेठीजी टिकट की जांच करने की चामत्कारिक दलील देते हैं। इनाम घोषित हुए करीब पांच माह होने को आये। न तो इनाम मिला न भविष्य में मिलेगा, इसका आश्वासन दिया गया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द मुझे चेक भेजा जाये।'

५—स्टेट बैंक आफ इंडिया की इंदौर शाखा पो० बा० १३४ का टेटे ट्रस्ट के अध्यक्ष को लिखा २.१२.८५ का पत्र, जिसकी प्रतिलिपि साइकिया को भेजी गयी, 'बिना विलंब के साइकिया की इनाम की राशि रिलीज करें।'

६—साइकिया के भागीदार आरएस सेठी को दि० १३.१२.८५ को लिखा पत्र। इसकी प्रतिलिपि इस बार अध्यक्ष, एक्जीक्यूटिव कमेटी टेटे ट्रस्ट सुरेश गावड़े, ३९ वासुदेवनगर इंदौर को भेजी गयी, यह लक्षणीय है। लिखते हैं: '१० सितंबर '८५ के पत्र में आपने लिखा था कि टिकट की सत्यता सिद्ध होने पर इंटेटे ट्रस्ट आपको इनाम की राशि देगा। मैंने श्री सुरेश गावड़े को पत्र लिखा। उनका उत्तर आया कि विजेताओं को इनाम राशि आप देंगे, न कि ट्रस्ट। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि मैं आपसे अतिशीघ्र संपर्क करूं। उनके उस बिनतारीख के पत्र की प्रति आपको भेज रहा हूं।

मेरी कोई गलती न होने पर भी आज तक घोषित पुरस्कार की रकम से मुझे पांच माह से वंचित रखा गया है और भविष्य में पुरस्कार कब मिलेगा, इसका

आश्वासन तक नहीं दिया गया है। ट्रस्ट इंदौर से कहता है कि पुरस्कार दिल्ली से मिलेगा और आप दिल्ली से लिखते हैं कि पैसा इंदौर देगा। यह विलंब लाटरी अथारिटी द्वारा किया जा रहा है, इसका स्मरण रहे, (नोट—अनुबंध के अनुसार ४५ दिनों में विजेता ने पुरस्कार नहीं लिया, तो राशि एजेंट को मिलती है) और जल्द से जल्द चेक/ड्राफ्ट भेजें।'

७—साइकिया द्वारा २६.१२.८५ को लिखा गया यह पत्र इनाम देने में आनाकानी करने की विडंबना का स्पष्ट प्रमाण है। एक ही पते पर पत्र और प्रतिलिपि रजिस्टर्ड एडी से भेजी गयी है। पता है ३६ वासुदेवनगर, इंदौर। पत्र है वैभवशाली, रैफल समिति के नाम और प्रतिलिपि है अध्यक्ष एक्जीक्यूटिव समिति इंटेटे ट्रस्ट सुरेश गावड़े को, जिनका इसी बंगले में निवास है। लिखते हैं: '१३.१२.१९८५ को श्री सेठी को लिखे पत्र की प्रतिलिपि मैंने आपको रजिस्ट्री से भेजी थी। उसकी रसीद मुझे २३.१२.८५ को मिली। मैंने देखा कि वैभवशाली के नाम से किसी ने वह पत्र स्वीकृत किया है। पत्र मैंने ट्रस्ट के अध्यक्ष को लिखा था। आपकी भूल से या डाक विभाग की गलती से वह पत्र आपके पास चला गया। कृपया वह अध्यक्ष श्री सुरेश गावड़े को फौरन देने की कृपा करें और मुझे उसकी सूचना दें।

आयोजकों की बदनीयती के मारे, ऐसे और कई बदनसीब होंगे। स्मरण रहे कि जिस ड्रा के इनाम इन लोगों को नहीं मिल पाये हैं, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता १२ जुलाई, १९८५ को प्रदेश के तत्कालीन उद्योगमंत्री भारत सिंह ने इंदौर नाट्यगृह में की थी।

साइकिया की तरह अन्य कई विजेताओं के बैंकर्स ने अपने ग्राहकों को इनामी रकम दी जाये, ऐसे पत्र-तार ट्रस्ट को इंदौर के पते पर भेजे हैं। उन बैंकों की इंदौर शाखाओं ने अध्यक्ष सुरेश गावड़े के नाम पत्र भेजे हैं। संक्षेप में विवरण यों है:

१—स्टेट बैंक आफ इंदौर, प्रिंस यशवंतरोड शाखा १४.८.८५ को पत्र क्र० सी० एम० ३९५ द्वारा लिखता है कि बैंक की रायसेन शाखा ने हमें एए/११०३४० नंबर का टिकट भेजा है। एक लाख का पुरस्कार राजीव कांत शर्मा को मिला है। कृपया इनाम की रकम हमारी शाखा में जमा करने का कष्ट करें।

२—स्टेट बैंक आफ इंडिया, जीपीओ शाखा का २०.७.८५ का मेमो कि द्वितीय पुरस्कार मिले टिकट क्रमांक १२१७५६ की पांच लाख रुपए की रकम तुरंत हमारे खाते में जमा करें। उक्त इनाम प्राप्त किया है सीतापुर की श्रीमती शीला देवी, चंपादेवी और अमृता बाई ने। आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एवं विजेताओं के फोटो संलग्न हैं।

ऐसे कुल दस दस्तावेज हमारे पास हैं। यह पत्र व्यवहार १९८५ का है। इधर फरवरी १९८९ में और दो घपले अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिले। मप्र भाजपा अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा ने १७ फरवरी को भोपाल में एक मामला उजागर किया। संबलपुर, उड़ीसा के सत्यनारायण अग्रवाल को टिकट क्रमांक ५५०४९ पर पंद्रह लाख का पुरस्कार घोषित हुआ, जो उन्हें अब तक नहीं मिला है। २४, २५ फरवरी, १९८९ के फ्रीप्रेस, इंदौर ने भावनगर के अलाउद्दीन अजीजभाई नूरानी का केस छापा है। वैभवशाली लाटरी का दस लाख रुपए का घोषित इनाम उन्हें आज तक नहीं मिला है।

आयोजकों की बदनीयती के मारे, ऐसे और कई बदनसीब होंगे। स्मरण रहे कि जिस ड्रा के इनाम इन लोगों को नहीं मिल पाये हैं, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता १२ जुलाई, १९८५ को प्रदेश के तत्कालीन उद्योगमंत्री भारत सिंह ने इंदौर नाट्यगृह में की थी। मप्र लाटरी विभाग के संचालक स्वरूप सिंह पोर्ते और संयुक्त संचालक गुप्ता के निरीक्षण में हिमाचल प्रदेश की लाटरी के निवृत्त संचालक ओबेराय ने ड्रा को संचालित किया। भारत भर के टिकट बेचनेवाले २५ प्रतिनिधि और सैकड़ों नगरवासी भी उस समय उपस्थित थे। विजेताओं को धोखा देने के साथ-साथ आयोजकों ने उपस्थित लाटरी संचालकों की आंखों में भी धूल झोंकी।

अय्यर एंड संस के दस्तावेज के मुताबिक १५ मई, १९८५ तक भारतलक्ष्मी सुपर बंपर ड्रा के ५० रुपए के ५६५७९३ टिकट भारत भर में ७५ एजेंटों द्वारा बेचे गये थे। अर्थात् २ करोड़ ८२ लाख ८९ हजार ६५० रुपए संचालकों के पास जमा थे। ड्रा खुलने में अभी ५७ दिन थे। उनमें और एक करोड़ रुपए की आय हुई होगी। इतनी धनराशि मिलने के बावजूद विजेताओं को एक पाई तक नहीं दी गयी। एक और बात का दुख है। संचालक इंदौर के और ड्रा इंदौर में हुआ। अब ऐसे में यदि सारा देश इंदौर को 'फ्राड' शहर मानने लगे, तो क्या दुख नहीं होगा?

—ब०पो०

अभय : *मैं उनके निराधार प्रचार की परवाह ही नहीं करता। एजेंट की अनियमितताओं को लेकर जब हम स्वयं अदालत में गये हैं, तब गैरों को हम क्यों सफाई दें? एजेंट भी यह तो नहीं कह रहा है कि वह इनाम देना नहीं चाहता।*

मैं : *एजेंटों में से अभी दिल्ली में कौन है?*

अभय : *अभी कोई नहीं है।*

मैं : *श्रीमती सबरवाल हैं ना?*

अभय : *हैं, मगर उन्होंने मकान बदल दिया है। नया पता हमारे पास अभी नहीं है और अब उनके खिलाफ मामले भी नहीं बचे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली शाखा ने लाजपतनगर थाने में झूठी गारंटी का जो मुकदमा दायर किया था, वह अब इंदौर ट्रांसफर हुआ है।*

मैं : *बैंक ने एजेंट के साथ ट्रस्ट पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है ना?*

अभय : *मगर हमने एजेंट पर यहां, इंदौर में मुकदमा दायर किया है।*

मैं : *एजेंट अय्यर एण्ड संस भारत के नक्शे पर कहीं हैं क्या? उनका कोई पता?*

अभय : *नहीं, इसलिए कि वह भागीदारी अब खतम हो गयी है। मगर आप श्रीमती सबरवाल से मिल सकते हैं। उनके वकील से उनका नया पता पूछकर आपको बता दूंगा।*

मैं : *अखबारों में आपके खिलाफ लॉटरी कांड के अलावा भी बहुत कुछ छप रहा है। सिर्फ दो विषयों पर पूछना चाहूंगा। भोपाल में 'नई दुनिया' के पास १६ बंगले हैं क्या?*

अभय : *सिर्फ छह बंगले हैं और स्टाफ की संख्या है १३०।*

मैं *इंदौर नगर निगम द्वारा निर्मित नेहरू स्टेडियम में टेटे के पास दो हाल और चार कमरे हैं, उसका क्या आठ लाख रुपया किराया आप पर चढ़ा हुआ है?*

अभय : *तो निगम वसूल क्यों नहीं करता? जब श्री भंवरसिंह शेखावत स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, अब उन्होंने वसूल क्यों नहीं किया? हमने खुला ऑफर दिया है कि निगम अदालत में जाये और वसूल करे।*

सुरेश गावड़े : *वसंता, मैं बताता हूं। निर्माण के बाद स्टेडियम बिलकुल खाली पड़ा था। १९६४-६५ में कमिश्नर श्री सतीश शिंदे और एक अधिकारी महेंद्र त्रिवेदी मेरे पास आये। उन्होंने कहा कि खाली पड़े स्टेडियम में कुछ गतिविधियां शुरू करो, तो हम पर अहसान होगा।*

अभय : *नई दुनिया में फीचर्स छपे हैं कि स्टेडियम में ढोर चर रहे हैं। निगम ने हमें निःशुल्क जगह दी, यह निगम की पत्रिका 'नागरिक' में छपा है। इस विवाद को निपटाने हेतु एक वर्ष पूर्व प्रशासक ने किराया तय करके हमसे एक अनुबंध किया। तब से हम बराबर दे रहे हैं किराया।*

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड

पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

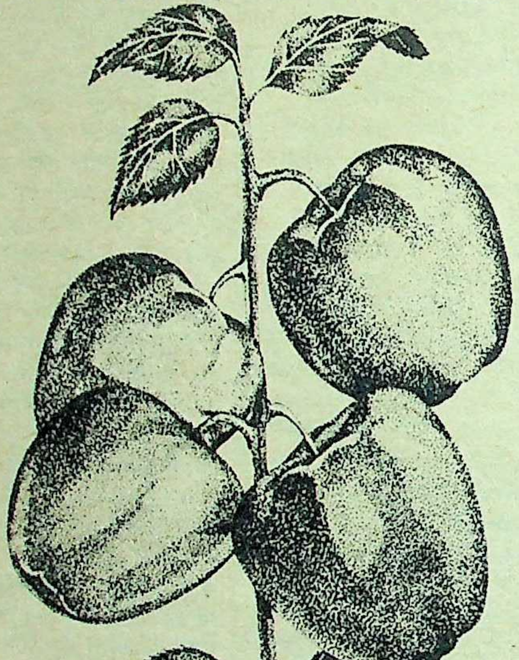

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) (xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

उद्योग की सेवा का 25 वाँ वर्ष

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
जॉली मेकर चेंबर्स नं. 2, 225, विनय के. शाह मार्ग, नरिमन पॉइंट, बम्बई 400 021.

Sobhagya-B/89 HN

अनुबंध पत्र

मेरे सामने नौ पृष्ठों का एक दस्तावेज है। ट्रस्ट और अय्यर एण्ड संस के बीच १३ फरवरी १९८५ को पंद्रह रुपए के स्टैंप पेपर पर हुआ अनुबंध पत्र है यह। संक्षेप में कुछ मुद्दे और कोष्ठक में उन पर मेरी टिप्पणी—

१- क्रमांक तीन के परिच्छेद में लिखा है कि ट्रस्ट या अन्य कोई भी अथारिटी एजेंट की बनाई हुई योजना में कतई दखलंदाजी नहीं करेगी। 'टिकट दर, इनामी राशि, योजना आदि में हम कोई आपत्ति नहीं उठायेंगे,' यह आश्वासन ट्रस्ट द्वारा एजेंट को दिया गया है। इन सबमें एजेंट जो निर्णय लेंगे, उसकी सिर्फ सूचना ट्रस्ट को देंगे।

(यानी ट्रस्ट बिलकुल बेसहारा और एजेंट के हाथ की कठपुतली बन गया।)

२- चौथे परिच्छेद में करार हुआ कि पहले ड्रा के संचालन में एजेंट से त्रुटियां हुईं, तो भी ट्रस्ट अगले दो ड्रा का अनुबंध अन्य किसी एजेंट से नहीं कर सकता।

मप्र सरकार के वित्त-विभाग ने क्रमांक १४६०/३६२७/८६/ नि-३/चार दिनांक २६ जुलाई, १९८४ को खेल प्रशाल निर्माण वास्ते ८० लाख रु० संग्रहीत करने के लिए लाटरी के तीन ड्रा निकालने की (पूर्णत: करमुक्त) विशेष अनुमति प्रदान की (ट्रस्ट को या अय्यर एण्ड संस को?)।

३- दसवें परिच्छेद में यह तय किया गया कि एक हजार रुपए या कम के इनाम एजेंट देंगे, एवं एक हजार से ऊपर के समस्त इनाम उचित आयकर काटकर, ट्रस्ट विजेताओं को देगा। ग्यारहवां परिच्छेद कहता है कि ५० प्रतिशत टिकट बिकते ही उस राशि में से इनामी धन का आधा हिस्सा एजेंट ट्रस्ट के पास जमा कर देगा। वह जमा न करने तक बचे हुए ५० प्रतिशत टिकटों की बिक्री एजेंट शुरू नहीं करेगा। एजेंट ट्रस्ट को आश्वस्त करता है कि वह प्रत्येक ड्रा खुलने के पूर्व उक्त राशि ट्रस्ट के पास जमा करेगा।

(यही वजह है कि ट्रस्ट उस पर हो रही आलोचना की अग्नि वर्षा से बेफ़िक है। अनुबंध के अनुसार एजेंट ने इनाम की रकम ट्रस्ट के पास जमा की ही नहीं, तब वह बेचारा कहां से देगा? लेकिन मुद्दे एक और दो स्पष्ट इंगित करते हैं कि एजेंट की पैसा देने की नीयत ही नहीं थी।)

४- बारहवां मुद्दा कहता है कि लाटरी संचालन, आर्थिक उत्तरदायित्व और ट्रस्ट को रायल्टी की राशि देने की बाबत समस्त कानूनों का एजेंट सख्ती से पालन करेगा, मगर मुकदमेबाजी की संपूर्ण जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी।

(अब कई मुकदमे लगे हैं और एजेंट को दोषी ठहराकर ट्रस्ट उनसे बचना चाहता है, जो अनुबंध के अनुसार गलत है।)

५- चौदहवां मुद्दा लावारिस इनामी राशि बाबत है। इनाम घोषित होने के दिन से अगर ४५ दिनों के अंदर विजेता अपना इनाम नहीं लेता है, तो वह धन एजेंट का हो जायेगा। एजेंट को लाटरी टिकट विजेता मानकर ट्रस्ट वह रकम उसके सुपुर्द कर देगा।

(पिंगपांग की गेंद की तरह विजेताओं के पत्रों को इंदौर-दिल्ली के बीच जो टप्पे खिलाये गये, वह सिर्फ ४५ दिनों की मियाद खतम हो जाये, इस वास्ते ही। जो पत्र ४५ दिनों के भीतर एजेंट को मिले, उनके जवाब में आयकर सर्टिफिकेट, टिकट की फोटोस्टेट प्रति विजेता के तीन फोटो, यहां तक कि इनाम प्राप्त हो गया है, इसकी अग्रिम रसीद तक मंगवाई गयी। डिब्रूगढ़ के साईकिया जब उन सब शर्तों को पूरा करने में सफल हो गये, तब उनके टिकट की मुद्रण विशेषज्ञ से जांच करवाने का मुद्दा एजेंट ने उठाया। देखिये लेख 'जिनके नसीब फूटे...'।

६- तीन भागों में बंटा हुआ १६वां परिच्छेद बैंक गारंटी के विषय में है। एजेंट कुल ३५ लाख रुपए की बैंक गारंटी ट्रस्ट को देगा। एजेंट विजेताओं के इनाम न दे सकने की स्थिति में फंसा, तो ट्रस्ट उस ३५ लाख में से विजेताओं के इनाम बांटेगा।

(एजेंट ने दिल्ली की पंजाब नेशनल बैंक, लाजपतनगर शाखा की ३५ लाख की गारंटी ट्रस्ट को दी। वह बोगस थी, इसका सविस्तार वर्णन 'ट्रस्ट को चूना यों लगा' लेख में पढ़ें।

७- इस अनुबंध में अगर परिवर्तन या संशोधन करना पड़े, तो ट्रस्ट और एजेंट इन दोनों पक्षों की सहमति से ही होगा, यह है परिच्छेद क्रमांक २२।

(अनुबंध पत्र में यह मुद्दा पढ़ते ही मैंने अभय छजलानी को फोन करके पूछा कि अनुबंध में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? उन्होंने कहा, "नहीं, १३ फरवरी १९८५ को हुआ अनुबंध ही अब तक बरकरार है।

—व०पो०

मैं: *खेल प्रशाल बनने पर क्या आप स्टेडियम की जगह छोड़ देंगे?*

अभय: *इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता।*

वस्तुस्थिति: आठ लाख बकाये की खबर बेबुनियाद है। नि:शुल्क दिया गया, यह भी गलत है। अभ्यास हेतु सभागृह नि:शुल्क दिये गये, न कि कार्यालय के कमरे। मैदानी खेलों के लिये जिस प्रकार मैदान नि:शुल्क दिये गये, उसी तरह टेटे अभ्यास के लिये सभागृह भी नि:शुल्क दिये गये। दैनिक 'जनसत्ता' के ५ जून १९८५ के अंक में लिखे महेश पांडे के लेख में टेटे संबंधी परिच्छेद यों हैं, 'निगम ने किराये की न्यूनतम दर यानी २५ पैसे प्रति वर्गफुट प्रतिमाह के हिसाब से बकाया निकाला है। दस रुपया महीना पानी 'कर' लगाया है। टेबल टेनिस एसोसिएशन से १४५ और १३० महीने के कुल ३ लाख २७ हजार ४७५ रुपए, इतना किराया वसूल करना है।'

मैं: *अभय विरोध का स्वर दिन-ब-दिन तीव्र हो रहा है। उससे तकलीफ तो होती होगी?*

अभय: *बहुत हो रही है?*

मैं: *ट्रस्ट और संगठन में और भी कई लोग हैं, तब आपको ही निशाना क्यों बनाया गया है?*

अभय: *मेरी ऐसी मान्यता है कि अखबारों द्वारा चलाया गया यह अभियान टेटे के खिलाफ नहीं है, बल्कि 'नई दुनिया' की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का एक अभियान है, क्योंकि 'नई दुनिया' की यह प्रतिष्ठा है कि वह बहुत सारे अच्छे कामों में साझेदार होता है। चूंकि अपने सारे पैसे और विभिन्न किस्म के विभिन्न स्तरीय व्यावसायिक दांव पेंच के बाद वे 'नई दुनिया' को मात नहीं दे सके, इसलिए 'नई दुनिया' से जुड़े व्यक्ति को बदनाम कर प्रकारांतर से 'नई दुनिया' की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो प्रकार के स्वार्थी तत्व हैं। यह एक संयोग है कि जब 'नई दुनिया' में शहर की अवैधानिक कालोनियों और नियमों का उल्लंघन करनेवाले उच्च भवनों के खिलाफ जिला अधिकारियों के बयान और कार्रवाइयों का ब्यौरा छपने लगा, तब उन अखबारों ने खेल प्रशाल को टार्गेट बनाकर प्रहार करना शुरू किया। जो लोग ऐसे व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, वे ही इन अखबारों के मालिक हैं। मैं कोई प्रमाण नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वे दूसरे नाम से धंधे करते हैं।*

मैं: *ये सिर्फ आपका बयान है या तथ्य?*

अभय: *तथ्य। ये जो इंदौर एवं अन्य शहरों में ऐसे कामों में लगे हुए हैं, उन्हें जब अपने अखबार चलाने का कोई और जरिया नहीं मिला और उनके उस व्यवसाय पर 'नई दुनिया' में लिखे जाने से प्रहार होने लगा, तो उन्होंने विषय बदलने के लिए और लोकमत बदलने के लिए झूठी बातें छापने का सहारा लिया। जो अखबार मेरे खिलाफ ऐसा छाप रहे हैं, उन्हें मेरी चुनौती है कि अगर उनके पास प्रमाण हैं, तो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में उसे प्रस्तुत करें और मेरे खिलाफ मुकदमा चलायें।* ■

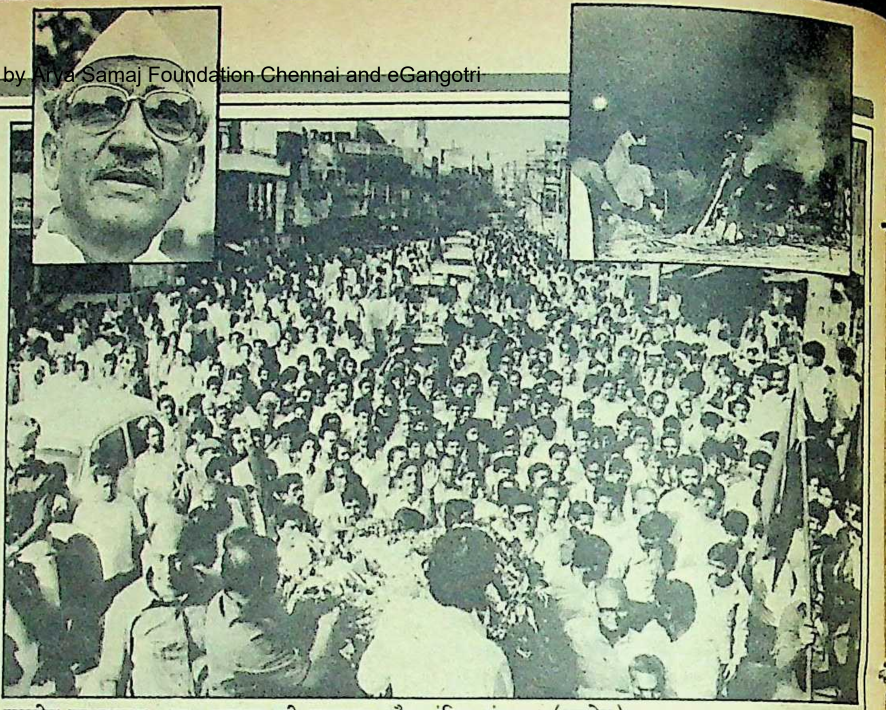

गमगीन इलाहाबाद: स्व० बहुगुणा की शवयात्रा और अंतिम संस्कार (इनसेट)

चोटी पर पहुंचने में बहुगुणा माहिर थे

पीडी टंडन

उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए पहाड़ी इलाके, गढ़वाल की गरीबी का ललकारा हुआ एक लड़का, करीब ५० वर्ष पहले इलाहाबाद में पढ़ने आया था। उसने १९३७ या ३८ में मुझे अपने विद्यार्थी साथियों के साथ मोहम्मद अली जिन्ना को बमरौली हवाई अड्डे पर काले झंडे दिखाते देखा था और 'जिन्ना वापस जाओ' के नारे लगाते सुना था। "वहीं पर मैंने आपको पहली बार देखा था और उसी दिन आपसे मिलने के लिए इच्छुक था। मगर मुलाकात कई साल बाद हो सकी थी," हेमवती नंदन बहुगुणा ने मुझे १९४३ में नैनी सेंट्रल जेल में बताया था। वहीं पर हमारी उनसे पक्की दोस्ती हो गयी थी। वे नेता बन चुके थे और कांग्रेस के कुछ बागियों के साथ उन्होंने १९४२ में जोरदार भूमिगत कार्य किया था। उनके जेल जीवन की कुछ बातें आगे बताऊंगा।

बहुगुणा बड़े डट कर काम करनेवाले व्यक्ति थे। बेतहाशा थी उनमें हिम्मत और कमाल का आत्मविश्वास। भूमिगत जीवन के दिनों की कड़ी मेहनत, खाने-पीने में लापरवाही के कारण उन्हें जेल में 'प्लूरिसी' हो गयी थी। जेल से छूटकर आने के काफी दिन बाद तक वे बीमार पड़े रहे। उन दिनों वे अरुणा आसफ अली के बड़े भक्त हो गये थे और हम थे विजय लक्ष्मी पंडित के पक्के अनुयायी। यद्यपि अरुणा का भी हम बड़ा आदर करते थे। वे अरुणा की बेइंतहा तारीफ करते थे और हम श्रीमती विजय लक्ष्मी की प्रशंसा के पुल बांधते थे। इसी को लेकर कभी-कभी हम दोनों में झड़प भी हो जाती थी। अच्छे होने के बाद वे जोश-खरोश से मजदूर संघों के लिए काम करने लगे। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वे विधानसभा सदस्य बने तथा गोविंद वल्लभ पंत सरकार में उन्हें उपमंत्री का पद पहली बार दिया गया। वे डाकगाड़ी की तरह राजनीतिक पटरियों पर वर्षों तक भागते रहे। केंद्र में कई बार मंत्री हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भी।

चाहे वे सत्ता में हों या सत्ता के बाहर, बहुगुणा राजनीतिक सिंह की भांति सदा दहाड़ते रहते थे। जब किसी के कंधे पर हाथ रख देते थे, तो वह व्यक्ति यह कहता मालूम होता था, "हाथ कंधे पर रख दिया मेरे, अब कमी किस बात की।" वे अपने राजनीतिक विरोधियों से सचेत रहते थे और उन्हें पछाड़ने की फिराक में भी, मौका आने पर उन्हें रगड़ भी देते थे। मगर व्यावहारिक होने के नाते वे अपने विरोधियों से भी बड़ी अच्छी तरह मिलते-जुलते थे।

सत्ता से बाहर होने पर भी वे कभी हिम्मत नहीं हारते थे। तोड़-फोड़ करने, मेल-मिलाप कराने, सत्ता में शान से लौट कर आ जाने का प्रयास करते रहते थे और देर-सबेर कामयाब होते ही थे। उनमें अहं काफी था। जिस बात पर डट जाते थे, उस पर अटल रहते थे, भले ही नतीजा कुछ भी निकले। जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि केके बिरला को संसद में नहीं जाने दूंगा और उन्होंने यह करके भी दिखा दिया। यद्यपि इंदिरा गांधी के आदेश थे कि बिरला को समर्थन दिया जाये।

जिन दिनों जय प्रकाश नारायण इंदिरा सरकार की जड़ खोदने में लगे हुए थे, उस समय मुख्यमंत्री बहुगुणा ने जेपी के उत्तर प्रदेश दौरे के समय उन्हें राज अतिथि बनाया था। जिन दिनों संजय गांधी की सारे देश में तूती बोल रही थी, उस समय बहुगुणा ने उन्हें अपने पास न फटकने दिया और उनकी डट कर मुखालफत की। [illegible] पर उन्हें मुख्यमंत्री-पद से हाथ धोना पड़ा। मगर डटे रहे बहुगुणा, इंदिरा का राज खतम करने में। जगजीवन राम आदि को मिलाकर १९७७ में इंदिरा सरकार को उन्होंने गिरा कर ही छोड़ा। मोरारजी की भी सरकार में मंत्री रहे, पर दबे नहीं। चरण सिंह सरकार में भी रहे और चौधरी साहब से भी टक्कर लेते रहे। बाद में दोनों मिल गये और बहुगुणा लोकदल में चौधरी के उत्तराधिकारी हुए। उनके बाद उन्होंने अजीत सिंह से भी मोर्चा लिया। लोकदल के दो टुकड़े हो गये। विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़ कर आये और उनकी सारे देश में हवा बंधी।

जून १९८८ में इलाहाबाद में चुनाव हुआ और उनकी विश्वनाथ प्रताप से भी ठन गयी। वे मेरे बहुत समझाने पर भी यह भुला न पाये कि विश्वनाथ प्रताप के मुख्यमंत्रित्व काल में जब वे कांग्रेस के खिलाफ गढवाल से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस को चारों खाने चित्त मारा था, तब चुनाव के दौरान उनके साथ कितना बुरा बरताव किया गया था। एक दिन अपनी टांग की चोट दिखाते हुए उन्होंने कहा था, "टंडन भाई, आप हमें समझाते हैं कि हम विश्वनाथ से झगड़ा न करें। आप कहते हैं इंदिराजी से झगड़ा न करो। मैं ऐसा करके अपनी हस्ती मिटा लूं। देखो मेरे पैर की चोट। मैं विश्वनाथ को कैसे भुला सकता हूं। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता।" उन्होंने विश्वनाथ से बदला ले ही कर छोड़ा और जनता दल को झकझोर ही दिया। विश्वनाथ के प्रभाव को हटाने में उनका बड़ा हाथ था। बहुगुणा ने पिछले कुछ महीनों में खुद भी झटके खाये। मगर वे गिरकर उठने में माहिर थे। उनके विरोधी कहने लगे कि बहुगुणा का राजनीतिक जीवन अब समाप्त हो जायेगा। इन लोगों को बहुगुणा की बहुआयामी क्षमता तथा अंदरूनी ताकत का अंदाजा नहीं था। [illegible] योद्धा बहुगुणा अकेले लगभग सभी दलों के

शीर्ष नेताओं से लड़ते ही रहे और लखनऊ मे इतनी बड़ी रैली आयोजित कर दी कि लोगों ने दांतों तले उंगुली दबा कर पुनः कहना शुरू कर दिया, "अरे बाप रे बाप, पछाड़ खाये हुए बहुगुणा आखिर फिर उभर ही आये और इतनी जबरदस्त रैली को संबोधित किया।" इसका कारण था बहुगुणा का लोगों पर व्यक्तिगत प्रभाव।

कमलापति त्रिपाठी की तरह बहुगुणा भी लोगों को उनके नाम से पुकारते थे। उनके त्रिपाठी से अकसर मतभेद होते हुए भी बहुगुणा उन्हें पिता तुल्य मानते थे और जब कभी भी उनसे मिलते थे, तो चरण स्पर्श करते थे। बहुगुणा ने स्वयं कहा है कि त्रिपाठी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके वे चरण स्पर्श करते हैं तथा करते रहेंगे। मुझसे तो वे अकसर कहा करते थे, "टंडन भाई, त्रिपाठीजी को लखनऊ में लाकर बिठा दो। उनसे कहो, वे स्वयं कुछ न करें। केवल अपने पैर छुलवाते रहें। उत्तर प्रदेश सरकार का खातमा अगर छह महीने में न कर दूं, तो मेरा नाम नहीं।" मैं हंसता था और कहता था, "मैं कैसे पंडितजी को लखनऊ में बिठा सकता हूं और अपनी पार्टी खतम कराने में दिलचस्पी ले सकता हूं।" उनका उत्तर होता था, "बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी, चुनाव आने दो।"

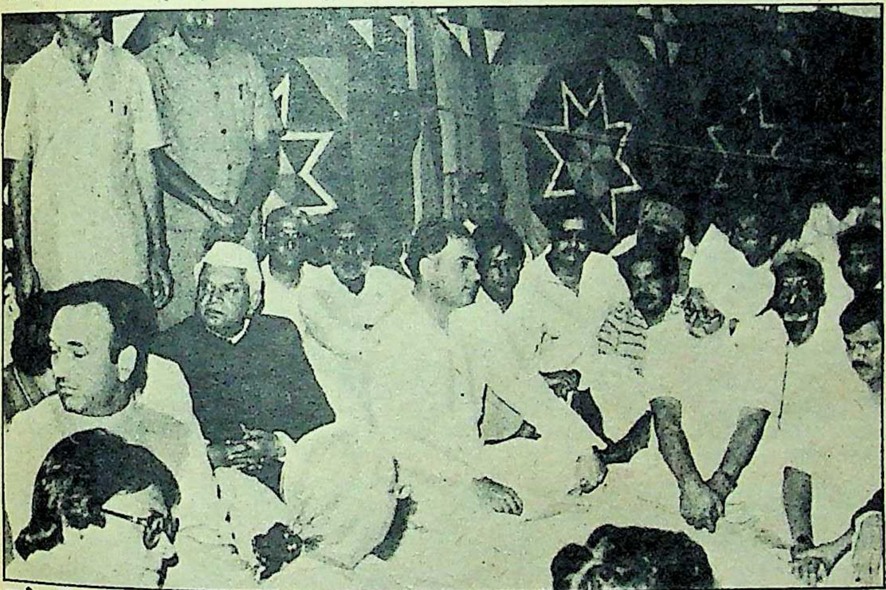

सभी पहुंचे : शीर्ष नेता शोक में शामिल

छाया : अनूप मेहरोत्रा

दिलचस्प व्यक्तित्व : बहुगुणा के राजनीतिक जीवन की एक रंगीली बहकानेवाली, भ्रम में डालनेवाली दिलचस्प कहानी है। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी विश्वसनीयता खतम हो गयी है और जनता का उनसे विश्वास हट गया है। उनकी मौत ने साबित कर दिया कि यह बात कितनी गलत थी। जनता उनके जैसे राजनीतिक पटेबाज के हथकंडे खूब अच्छी तरह समझती थी और जानती थी कि उन्होंने कई बार पार्टियां केवल मजबूरी में बदलीं। स्वाभिमान उनके लिए नेताओं के प्रति वफादारी से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। उनका अहं उन्हें मजबूर करता था कि सिर न झुकायें, चाहे मिट जायें।

मैंने तो कई लोगों के जनाजों में शिरकत की है, कई राजनीतिक हस्तियों की अस्थियों को विसर्जित होते देखा है, मगर गांधी, नेहरू और इंदिरा को छोड़कर मैंने ऐसा सच्चा गहरा गम कभी नहीं देखा, जैसा उस दिन बहुगुणा के पार्थिव शरीर के बमरौली हवाई अड्डे पर उतरने के समय दिखायी दिया था। हजारों चेहरों पर गम की गहरी छाप थी। सैकड़ों चेहरों पर बहुगुणा के अहसानों की मुहर लगी थी। बहुत से लोग तो फूट-फूट कर सिर्फ इसलिए रो रहे थे कि अब उनका कोई सहारा नहीं बचा था।

बहुगुणा में कुछ अवगुण तो थे ही, मगर कौन ऐसा इंसान है जो बुराइयों से परे हो। शेक्सपियर ने लिखा है, "अच्छे से अच्छे लोगों में दोष तो होते ही हैं।" बहुगुणा के केवल अवगुणों को लेकर मूल्यांकन करना एक निहायत मूर्खता का काम होगा। आजकल दो कौड़ी के दर्जनों नेता राजनीतिक आकाश में जोरों से भटकते-मंडराते दिखायी पड़ते हैं। उनको देखते हुए बहुगुणा एक हीरा था। जिसमें प्रशासनिक योग्यता थी, जो सच्चा दोस्त था, गरीब और पिछड़े वर्गों का मसीहा था, जनता का जानदार मददगार था।

एक दिन जनता शासन के दौरान मैं और वे दिल्ली में उनके आवास के लान पर घूम-घूम कर बातें कर रहे थे कि बहुगुणा ने कहा, "टंडन भाई, मैं एक बात के लिए इंदिराजी को कभी क्षमा नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे बेघर कर दिया।" मैंने टोकते हुए पूछा, "इतना बड़ा घर लिये बैठे हो और कहते हो बेघर कर दिया।" नाराज होकर उन्होंने उत्तर दिया, "मेरी राजनीतिक शिक्षा आनंद भवन में हुई। नेहरू के चरणों पर बैठकर मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या इसीलिए कि मैं इन प्रतिक्रियावादियों के साथ बैठ कर सरकार चलाऊं। मुझे शर्म लगती है, मगर मजबूरी है। कुछ कर नहीं पा रहा हूं नेहरू विरोधियों के खेमे में।" बहुगुणा नेहरू के बड़े जबरदस्त हिमायती रहे।

एक और घटना के बारे में सुनिए, जो कुछ ही महीने पुरानी है। एक दिन मुझे एक जिम्मेदार आदमी ने बताया कि बहुगुणा एक लंबी गाड़ी में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के घर जा धमके, जबकि वहां किसी को इसकी खबर न थी। उसी दिन दिल्ली से कुछ इंका पर्यवेक्षक भी वहां आये हुए थे। तिवारी बहुगुणा को देखते ही शायद कुछ सिटपिटा गये, क्योंकि वहां दर्जनों कांग्रेसी 'कनफुक्के' भी मौजूद थे। जो तिवारी के पैर छूने के बाद बाहर जाकर उड़ा सकते थे कि वे बहुगुणा के साथ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुगुणा ने तिवारी से कहा, "आप एक बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री हैं और मैं हूं बहुगुणा। बिना समय लिये आ गया हूं। यदि आपके पास समय न हो, तो फिर आ जाऊंगा। मुझे लोगों की तकलीफों के बारे में तो आप लोगों को बताना ही है।" जरूरत से ज्यादा नम्र स्वभाव के तिवारी ने बड़ी नम्रता से बातचीत जोर-जोर करना शुरू कर दिया, जिससे हर कोई सुन ले कि क्या बातें हो रही हैं? राजनीति में अच्छे राजनीतिक कदम फूंक-फूंक कर रखते हैं, तिवारी तो एकदम ठंडा करके कदम उठाते हैं। उस दिन की खास बात यह थी कि एक पुराना जोरदार मुख्यमंत्री आज के मुख्यमंत्री के सामने झोली लेकर गरीबों को राहत दिलाने के लिए गया था और इसमें उसने कोई अपमान नहीं समझा। ऐसा था बहुगुणा का जनता से लगाव।

बहुगुणा का सबसे बड़ा गुण था—लौट-फिर कर चोटी पर पहुंच जाना, चाहे वह सत्ता का महल हो, चाहे विरोधियों का छप्पर। कभी दायें से कभी बायें से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी रेंगकर, कभी छलांग मारकर, कभी दौड़कर चोटी पर पहुंच जाने में वे माहिर थे। उनमें रफी अहमद किदवई तथा चंद्रभानु गुप्त की काफी खूबियां थीं। मदद करने में कभी चूकते नहीं थे। उलझे मामलों को सुलझाने में माहिर थे।

जो लोग कहते थे कि अपने अंतिम दिनों में बहुगुणा का पत्ता राजनीति से कट गया था, वे यह भूल जाते थे कि कभी-कभी दिन में बादल छा जाते हैं, किंतु सूरज को वे हमेशा के लिए नहीं ढंक सकते। यदि वे अमरीका से स्वस्थ होकर लौट पाते, तो वे फिर वक्त के सूरज की तरह रात के अंधेरे को समाप्त करके पुनः राजनीति गगन में छा जाते। वे एक मायने में राजनीति में अकेले पड़ गये थे। मगर राजनीतिक जंगल में वे जख्मी शेर की तरह अपने विरोधियों का शिकार करने पर तुले हुए थे। देर संबेर कामयाब जरूर होते। या तो कोई समझौता हो जाता, या उनके कुछ विरोधियों का सफाया हो जाता। उनकी राजनीतिक शाम दर्जनों बड़े राजनीतिज्ञों के दिन के उजाले से कहीं ज्यादा रौशन थी। ■

उत्तर प्रदेश कांग्रेस

लखनऊ का गुस्सा मुरादाबाद में फटा

१० फरवरी को गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस-इ नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ जो बरताव किया था, उसके बुरे नतीजे मुरादाबाद में उस समय निकले जब गुलाम नबी आजाद के सम्मान में वहां रैली आयोजित हुई। आजाद को मुरादाबाद में किस उद्देश्य से किन लोगों ने आमंत्रित किया था?

जिस मुरादाबाद को गुलाम नबी आजाद के लिए 'सुरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र' बनाने की योजना थी, वहां कांग्रेस-इ की रैली में जूते चले, आजाद को आलपीन चुभोकर जलील किया गया। किंतु क्या यह अचानक हुआ? पार्टी में अवांछनीय तत्वों को बढ़ावा दिये जाने के खिलाफ उठ खड़े हुए कांग्रेसी बताते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के नेताओं-कार्यकर्ताओं को उपेक्षित तथा अपमानित किये जाने की अवश्यंभावी परिणति थी। पार्टी के लोग १० फरवरी को लखनऊ में हुई घटना को जरा भी भूल नही पाये हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के प्रायः सभी बरिष्ठ मंत्रियों को पंडाल के एक कोने में मंच से काफी दूर फर्श पर बिठाया गया था। बलराम सिंह यादव ऐलान कर चुके थे, "हमारा चांद (राजीव गांधी) निकला है और अब हमारी ईद है।" तभी राज्यमंत्री जगदंबिका पाल 'चांद' के आड़े आ गये थे। पं० लोकपति त्रिपाठी ने दूर कोने से चिल्लाकर कहा था, "पालजी, जरा सामने से हट जायें जिससे हम भी अपने चांद के दर्शन कर सकें।" चंद्रदर्शन के बाद जब पंडाल जय-जयकार के तुमुल घोष से गूंज रहा था, तभी 'चोप्प चोप्प' की आवाज आयी थी। एक गुस्से भरी खामोशी तन गयी माहौल पर। फिर आवाज आयी, "उत्तर प्रदेशवाले इसी भाषा के आदी हैं।" कांग्रेस के महासचिव, पार्टी के प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश पार्टी के प्रभारी और सांसद गुलाम नबी आजाद बोले जा रहे थे, "उत्तर प्रदेश आता हूं, तो यहां वालों से ऐसे ही बात करता हूं, वे यही भाषा समझते हैं।"

हजरतमहल पार्क, लखनऊ की १० फरवरी की इसी घटना के साथ शुरू होती है क्षोभ से भरी वह कहानी जो आजाद की किस्मत के लिए कफस बन जाती है। प्रदेश के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मंत्रियों तथा विधायकों ने जब देखा कि जगदंबिका पाल और कांग्रेस के संयुक्त सचिव सिराज मेहंदी ने मंच पर राजीव गांधी को घेर लिया है और पंडाल में प्रदेश भर से आये कांग्रेस के जिला परिषद और पालिका अध्यक्षों, सेवादल के और पार्टी के अन्य हजारों कार्यकर्ताओं के सामने बड़े-बड़ों को पंडाल के कोने में धूल में पटक दिया गया है, तब उन्हें लगा कि यह सब पूर्वनियोजित था और अपमानित करने के इरादे से रचा गया था।

असंतोष का धमाका: कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर तो असंतोष था ही कि मंत्रिपरिषद

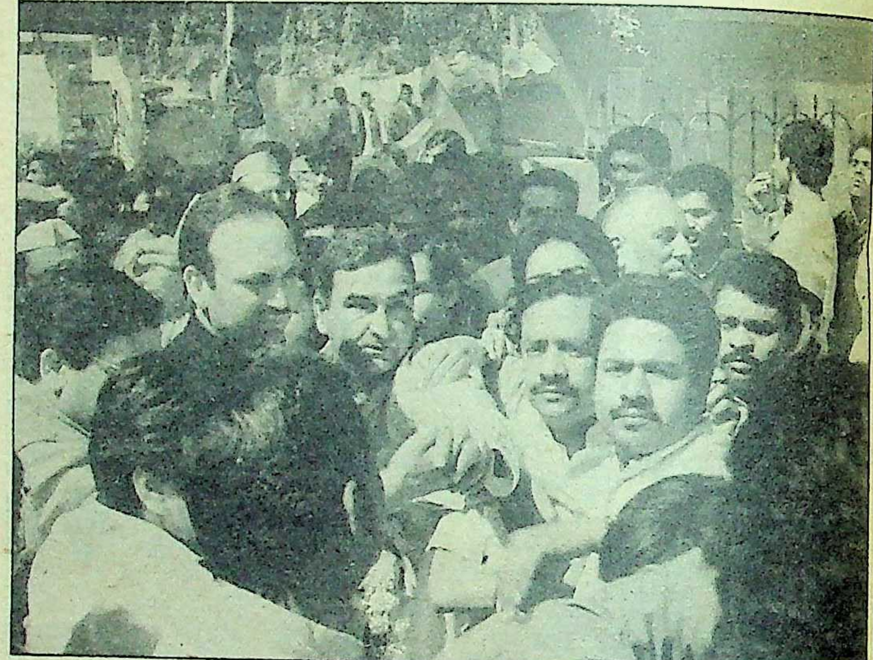

जान आफत में: आजाद घिरे हुए

छाया: आरके रामू

मंच पर अराजकता: मुरादाबाद रैली का एक नजारा

और संगठन में बहुत से अनधिकारी व्यक्ति घुस गये हैं। पर तब असंतोष भीतर ही भीतर था। १० फरवरी की घटना से वह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष बलराम सिंह यादव इस उबलते और फटते-फैलते असंतोष से विशेष रूप से चिंतित हुए। उन्होंने छह दिन बाद १६ फरवरी को पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलायी। उद्देश्य यह था कि पार्टी के ढांचे के गठन पर कुछ चर्चा होगी, कुछ कहा-सुना जायेगा, खाना-पीना होगा और जख्मों पर मरहम लगा दिया जायेगा। पर बैठक शुरू होते ही गुस्सा फिर बरसा। कई विधायकों ने आलोचना के स्वर को गाली-गलौज के स्तर तक पहुंचा दिया। कहा गया, "संगठन पर अपराधकर्मी और सरकार पर सत्ता के दलाल कब्जा करते जा रहे हैं। मंत्री ही पार्टी के उम्मीदवारो को हरा रहे हैं। भ्रष्टाचार का यह आलम है कि मंत्री के चपरासी और ड्राइवर को बख्शीश दिये बिना मंत्री से भेंट नहीं हो सकती। विधायकों के कहने पर अधिकारियों के तबादले नहीं किये जाते। मंत्री स्वयं तबादले करने और मोटी रकम वसूलते हैं।"

आग में घी: बलराम सिंह यादव यह सब सुनने का साहस न बटोर सके। बैठक डेढ़-दो घंटे में ही खतम हो गयी। पर यह संकेत देने से भी बलराम सिंह यादव नहीं चूके कि आलोचना का उन पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने उसी दिन पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि सिराज मेहंदी को पार्टी के कार्यकर्ता तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंप दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में 'कैडर बिल्डिंग' प्रभारी सिराज मेहंदी ही होंगे। उनके अतिरिक्त और कोई प्रशिक्षण-शिविर आयोजित नहीं करेगा।

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव की इस घोषणा ने आग में घी का काम किया। विधायक तो सवेरे आयोजित डेढ़-दो घंटे की बैठक से यह पीड़ा लेकर लौटे थे कि अब हमारी सुननेवाला कोई नहीं। कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष मणिशकर पांडे को लगा कि अब उनके घर में भी 'डाका' डाला जा रहा है। उन्होंने बयान जारी किया कि इलाहाबाद में सेवादल का जो प्रशिक्षण-शिविर आयोजित किया जा रहा है, वह पूर्ववत आयोजित होगा। 'कैडर बिल्डिंग' का कोई एक व्यक्ति प्रभारी नहीं है। पहले की ही तरह प्रत्येक क्षेत्र में इसके अलग-अलग प्रभारी होंगे।

गुलाम नबी आजाद को आधार बनाकर बलराम सिंह यादव, जगदंबिका पाल और सिराज मेहंदी की जो नयी चौकड़ी बन रही थी उसने १० फरवरी को अपने आपको 'चांद' के चौखटे के रूप में सत्ता और संगठन पर छा जाने की जो तैयारी की थी, मणिशंकर पांडे का बयान इस पर पहला प्रहार था। दूसरा प्रहार विधायकों ने हस्ताक्षर आंदोलन से शुरू किया। उन्होंने कहा, "हम यह आंदोलन राजीव गांधी और नारायणदत्त तिवारी के हाथ मजबूत करने के लिए शुरू कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद् गठित करने में तिवारीजी को कोई छूट नहीं दी गयी। भ्रष्ट, अयोग्य और सत्ता के दलालों को तिवारीजी के सिर पर थोप दिया गया है। यही हाल संगठन का है। वहां भी सब अलाय-बलाय भर गयी है। हम सरकार और संगठन दोनों को शुद्ध करने के उद्देश्य से यह आंदोलन चला रहे हैं।" उनकी मांग यह भी थी कि गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश के मामलों में बोलने और राय देने से रोका जाये और इस प्रदेश का दायित्व किसी और को सौंपा जाये।

१६ फरवरी की बैठक के बाद शुरू इस हस्ताक्षर अभियान ने जोर पकड़ा। दो-चार दिन में ही इस पर लगभग ८० विधायकों ने दस्तखत कर दिये। इस अभियान से मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी को चिंता हुई। एक जानकार सूत्र के अनुसार तिवारीजी ने तो एक प्रसंग में यहां तक कह दिया कि यदि यह अभियान मेरे विरुद्ध है और दो विधायक भी आकर मुझसे कह दें, तो मैं इस्तीफा देकर हट जाऊंगा। तिवारीजी की पीड़ा से हस्ताक्षर आंदोलन के नेताओं को भी कष्ट हुआ। तिवारीजी के साथ उनकी लंबी वार्ता हुई। विधायकों ने तिवारीजी को बताया, "हम तो आपकी और राजीवजी की रक्षा के लिए उठ रहे हैं।" तिवारीजी ने विधायकों को समझाया, "आपके इरादे चाहे जितने नेक हों, पर इस समय प्रदेश का राजनीतिक माहौल जैसा है, उसमें सही बात को भी गलत समझा जायेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फिलहाल ऐसा कोई काम न किया जाये।"

> **दिल्ली से समाचार आया कि गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं रहे। लखनऊ में बलराम सिंह यादव के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सिराज मेहंदी को 'कैडर बिल्डिंग प्रभारी' पद से हटा दिया गया है।**

क्षेत्र की खोज: तिवारीजी की सलाह मान कर विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान तो रोक दिया, पर अपने ही घर में अपमानित होने से जो घाव लगा था, उसका रिसना बंद न हुआ। इसी बीच समाचार आया कि गुलाम नबी आजाद के लिए अब महाराष्ट्र काफी गर्म हो चुका है। वे वासिम से लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं। पर अब न तो शरद पवार उन्हें चाहते हैं और न अंतुले उनका साथ देने को राजी हैं। इस स्थिति से परिचित गुलाम नबी आजाद अब उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित स्थान चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश लाने में बलराम सिंह यादव, जगदंबिका पाल और सिराज मेहंदी की विशेष दिलचस्पी है। इस दृष्टि से कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सुझाये गये हैं।

गुलाम नबी आजाद ने उत्तर प्रदेश के सभी ८५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का जायजा लेना शुरू किया है। इसी सिलसिले में मेरठ और मुरादाबाद के दौरे का कार्यक्रम बनाया गया। मेरठ से श्रीमती मोहसिना किदवई लोकसभा के लिए चुनी गयी हैं। जब तक वे स्वयं मेरठ नहीं छोड़तीं, तब तक गुलाम नबी आजाद उस पर मुंह चलाने की नहीं सोच सकते। अतः मुरादाबाद को टटोलना अधिक उपयुक्त समझा गया। इस मंडल के प्रभारी सिराज मेहंदी हैं। जगदंबिका पाल और सिराज मेहंदी की दूरगामी राजनीतिक योजना की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि गुलाम नबी आजाद उत्तर प्रदेश से लोकसभा में पहुंचें।

मंच पर मारपीट: मुरादाबाद में गुलाम नबी आजाद के सम्मान में रैली आयोजित करने और उन्हें थैली भेंट करने का कार्यक्रम तैयार करने के पीछे यह उद्देश्य भी था कि पालिका चुनाव में प्रतिपक्षी उम्मीदवार की जीत के बाद कांग्रेस उस क्षेत्र में बढ़ते अपने वर्चस्व का इजहार करना चाहती थी। मुरादाबाद से लोकसभा में पहुंचने के लिए पंक्ति में जो खड़े हैं, उनमें हाफिज मुहम्मद सिद्दीकी भी हैं। सिद्दीकी को शिकायत है कि उनके विरोध के बावजूद गुलाम नबी आजाद और उनके उत्तर प्रदेशीय 'शिष्यों' ने एक कमजोर घोड़े को मैदान में उतार दिया, जिसका समर्थन करने को कांग्रेसी कार्यकर्ता भी तैयार नहीं थे। इस घटना से कांग्रेस में फूट पड़ी है। अब सिराज मेहंदी ने गुलाम नबी आजाद की जान-पहचान बढ़ाने और जमाने के लिए जो आयोजन किया, उससे फूट और विरोध ज्यादा गहरा गया।

मुरादाबाद रैली में गुलाम नबी आजाद के पहुंचते ही उनके समर्थकों और विरोधियों में, जो पहले से ही एक-दूसरे से भिन्नाये हुए थे, हाथापाई शुरू हो गयी। गाली-गलौज के साथ जूते-चप्पलें भी चलने लगीं। झगड़ालू पक्ष मंच पर भी जा पहुंचे। वहां भी जूते चले। सिराज मेहंदी से माइक छीन लिया गया। जो 'अस्त्र' चल रहे थे, उनके निशाने गुलाम नबी आजाद और बलराम सिंह यादव भी बने। आजाद की पीठ में आलपीनें चुभोई गयीं। आजाद और यादव हड़बड़ी में मंच छोड़कर भागे। रैली भंग हो गयी।

इस तरह लखनऊ की 'चोप्प' का जवाब मुरादाबाद में दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोग जो भाषा समझते-समझाते हैं, यह उसकी एक बानगी थी। इसका परिणाम सामने आया। दिल्ली से समाचार आया कि गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं रहे। लखनऊ में बलराम सिंह यादव के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सिराज मेहंदी को 'कैडर बिल्डिंग प्रभारी' पद से हटा दिया गया है। तो क्या चौकड़ी टूट गयी है? क्या नाटक का भरत वाक्य बोला जा चुका है? पार्टी के जानकार लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी कहना फिलहाल सही नहीं है।

—रामपाल सिंह

पर्यटन का विकास

उत्तर प्रदेश का धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अपना विशेष स्थान है। यही कारण है कि यहां बड़ी संख्या में देश तथा विदेश से पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमणार्थ आते हैं और अनुपम आनन्द की अनुभूति लेकर वापस जाते हैं। उनके मानस पटल पर एक अमिट छाप बन जाती है, जिसका रसास्वादन वे जब चाहते हैं, कर लेते हैं और अद्वितीय सुख का आनन्द लेते हैं।

पर्यटकों की सुविधा के लिए तथा अधिकाधिक पर्यटकों को इस आनन्दातिरेक

गुलिस्तां पर्यटक काम्प
का उद्घाटन
श्री नारायण दत्त ति

गुलिस्तां पर्यटक काम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी

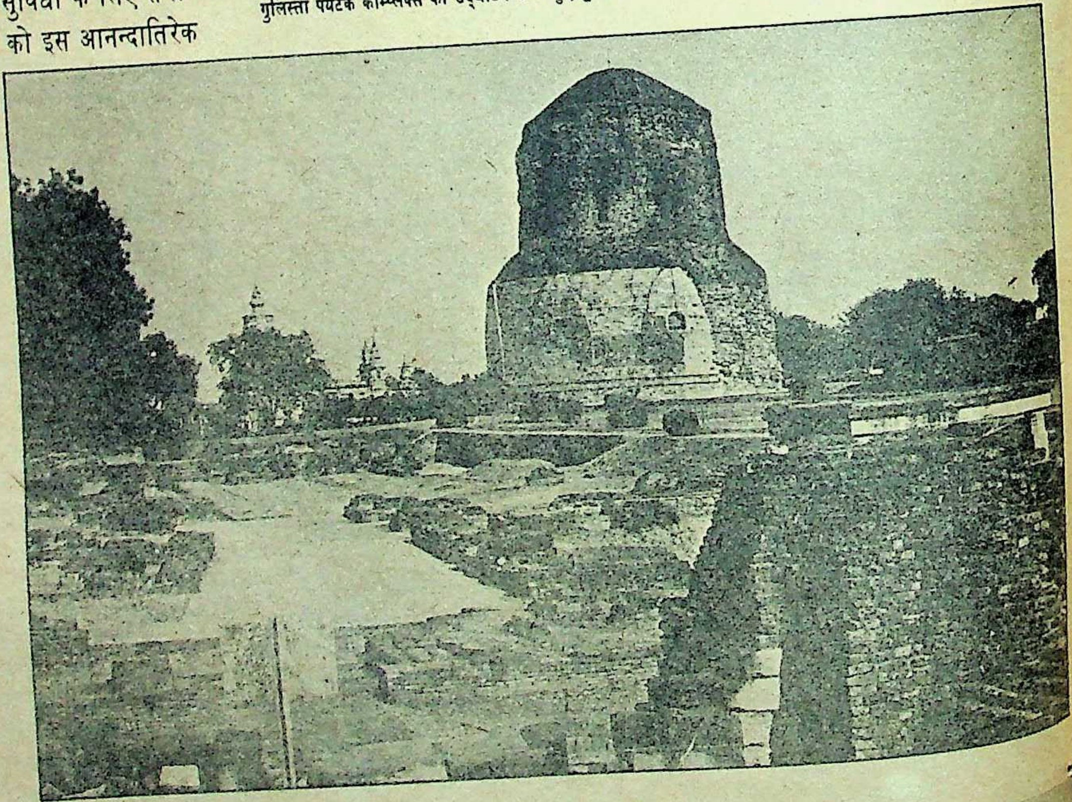

सारनाथ

से विभोर करने के लिए प्रदेश प्रशासन ने अनेक योजनाएं तथा दूरगामी कदम उठाये हैं। पर्यटन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन के बहुआयामी विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना आगरा के सौन्दर्यकरण की है। इसके अन्तर्गत ताजमहल के सामने यमुना नदी के तट पर लगभग ३४० एकड़ भूमि ताज नेशनल पार्क के निर्माण के लिए ली गयी है। यह पार्क देश का एक अद्वितीय पार्क होगा। इसके अतिरिक्त आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी में एक पर्यटन काम्पलेक्स का निर्माण पूर्ण हो गया है। पर्यटकों के आकर्षण को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से आगरा, नोयडा, नैनीताल, रानीखेत तथा लखनऊ में गोल्फ कोर्स को विकसित करने की भी एक योजना बनायी गयी है।

श्री पी०के० मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पर्यटन विकास निगम तथा निदेशक प्रोपीन प्रोडक्ट्स प्रा०लि० होटल निर्माण के अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करते हुए

होटल वीरांगना, झांसी

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को विकसित करने तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए गौचर तथा पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के निर्माण की योजना बनायी गयी है। ऐसी हवाई पट्टियां प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी बनायी जायेंगी, जिससे पर्यटकों को आरामदायक यात्रा सुलभ हो सके।

पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर मनोरंजन के साधन सुलभ कराने के लिए जोशीमठ के निकट औली में पर्यटन विकास की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जोशीमठ से औली के बीच चार किलोमीटर रज्जुमार्ग (रोपवे) का निर्माण, आवासीय तथा स्कीइंग आदि की

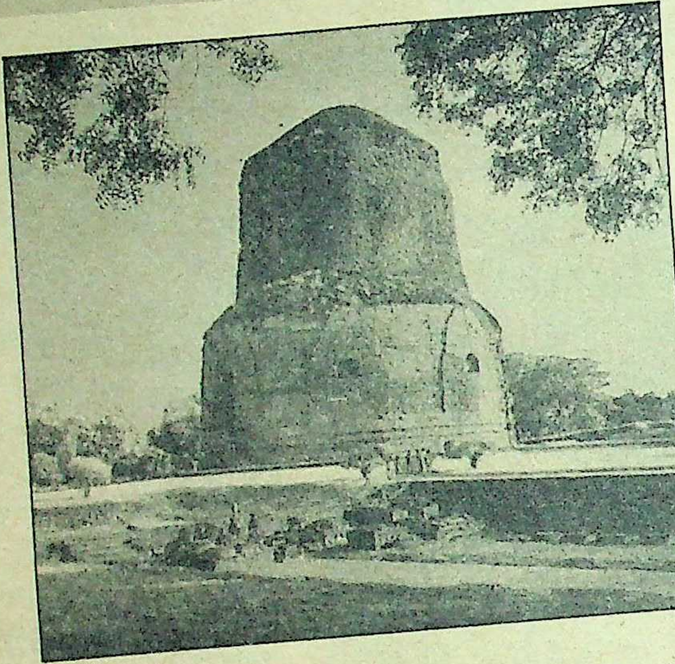

सारनाथ

लैपविंग मोटल एवं रेस्टोरेन्ट, शाहजहांपुर

सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इससे यहां शीतकालीन पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ स्थलों पर जलक्रीड़ा हेतु योजना पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत रिवर रैफ्टिंग, रोइंग व नौकाचालन आदि पर विशेष बल दिया जायेगा।

हिमाच्छादित व मनोरम पर्वतीय क्षेत्र में रज्जुमार्ग से यात्रा अत्यन्त आल्हादकारी होती है। इस उद्देश्य से राजापुर से मसूरी, गौरीकुण्ड से गरुड़ चट्टी, लक्ष्मण झूला से कुजापुरी तथा धुलीगाड़ से पुण्यागिरी स्थलों के बीच रज्जुमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है। इससे जहां दुर्गम यात्रा कम समय में सुविधापूर्ण ढंग से तय की जा सकेगी, वहीं प्रकृति की निराली छटा को निहारने की उत्सुकता के कारण पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में देश व विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मसूरी के निकट जार्ज एवरेस्ट हाउस (पार्क स्टेट) की लगभग १७३ एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। यहां पर एक छोटा पर्यटन नगर बसाया जायेगा, जिसमें पर्यटकों के लिए सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

पर्यटकों को अच्छी आवासीय सुविधा सुलभ कराने के लिए पर्यटन विभाग निरन्त प्रयास कर रहा है। इस कार्य के लिए वह निजी क्षेत्रों में होटल निर्माण करनेवालों को भी प्रोत्साहन दे रहा है। फलस्वरूप निजी क्षेत्र में होटलों के निर्माण से लगभग १४९० और अधिक शैयाओं के उपलब्ध

होने की आशा है।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण एवं सत्य-अहिंसा के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के अनुयायी हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रदेश में स्थित पावन स्थलों पर श्रद्धा सुमन अर्पण करने आते हैं। अतः अयोध्या, वाराणसी एवं वृन्दावन क्षेत्रों के विश्वव्यापी महत्व को देखते हुए इनके संरक्षण तथा विशेष विकास हेतु तीन विशिष्ट समितियां गठित की गयी हैं, जिससे इन स्थलों का द्रुतगति से विकास किया जा सके। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की भांति अयोध्या में राम की पैड़ी का निर्माण कराया जा चुका है। इसी प्रकार काशी के घाटों का पुनरुद्धार करवाया गया है। देश व विदेश के बौद्ध धर्म के अनुयाइयों और प्रशंसकों को अधिकाधिक सुविधायें सुलभ कराने के लिए बौद्ध परिपथ (वाराणसी-सारनाथ, गोरखपुर-कुशीनगर-सुनौली-पिपरहवा, नौगढ़ श्रावस्ती-गोंडा-अयोध्या-लखनऊ) के सर्वांगीण विकास की एक महायोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत बौद्ध स्थलों में आवास, यातायात तथा अन्य सुविधाएं सुलभ करायी जायेंगी।

बौद्ध परिपथ परियोजना में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए अच्छी एवं चौड़ी सड़कें, बिजली की उपलब्धता, आरामदायक साफ-सुथरे होटल एवं आवास गृहों की व्यवस्था की जा रही है। बौद्ध परिपथ के विकास के लिए भारत सरकार व जापान सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अन्तर्गत सड़क, होटल, मार्गीय सुविधा, बिजली, जल सम्पूर्ति के लिए जापान सरकार उत्तर प्रदेश एवं बिहार को सम्मिलित रूप से ९.२४४ बिलियन येन (लगभग १०० करोड़ रुपये) की सहायता प्रदान करेगी। जापान सरकार ने प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर गोरखपुर, वाराणसी तथा सारनाथ को चुना है।

कुशीनगर

औली में स्कीइग

अयोध्या के सांस्कृतिक विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी रामकथा पार्क योजना बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत लगभग ६०.४३ एकड़ भूमि ली गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत भगवान राम की ऐसी लीलायें प्रदर्शित की जायेंगी, जिससे भारतीय समाज की प्राचीन संस्कृति दृष्टिगोचर होगी। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रवचन हेतु स्टेज, वृक्षारोपण आदि का कार्य किया जायेगा। वह तीर्थयात्रियों के लिए अनोखा आकर्षण होगा। इसमें ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए भगवान राम के जीवन से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य एक्स्ट्रैक्ट्स होंगे। इस कार्यक्रम में भगवान राम से सम्बन्धित दर्शन पर विधिवत अधिक बल दिया जायेगा।

प्रदेश में पर्यटन महत्व के स्थलों का बाहुल्य है और पर्यटन का अपना अनोखा आनन्द और अनुभूति है। प्रदेश शासन यद्यपि पर्यटन के विकास और पर्यटकों की सुख-सुविधा के लिए अपेक्षित प्रबन्ध करने के लिए प्रयत्नशील है, फिर भी इस व्यवस्था में सुधार और विस्तार की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसी दृष्टि से प्रदेश प्रशासन दूरगामी परिप्रेक्ष्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश—बिहार सीमा विवाद

हिंसक टकराव की नौबत

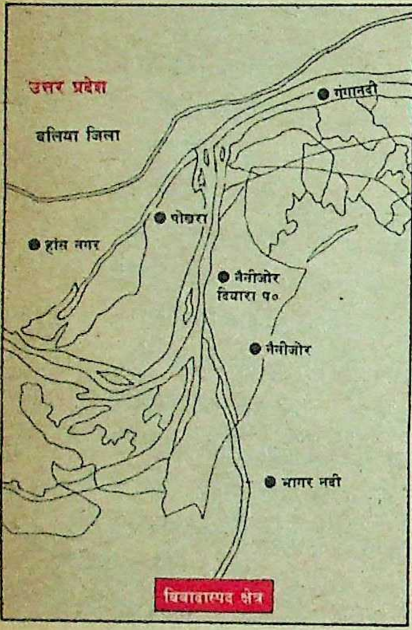

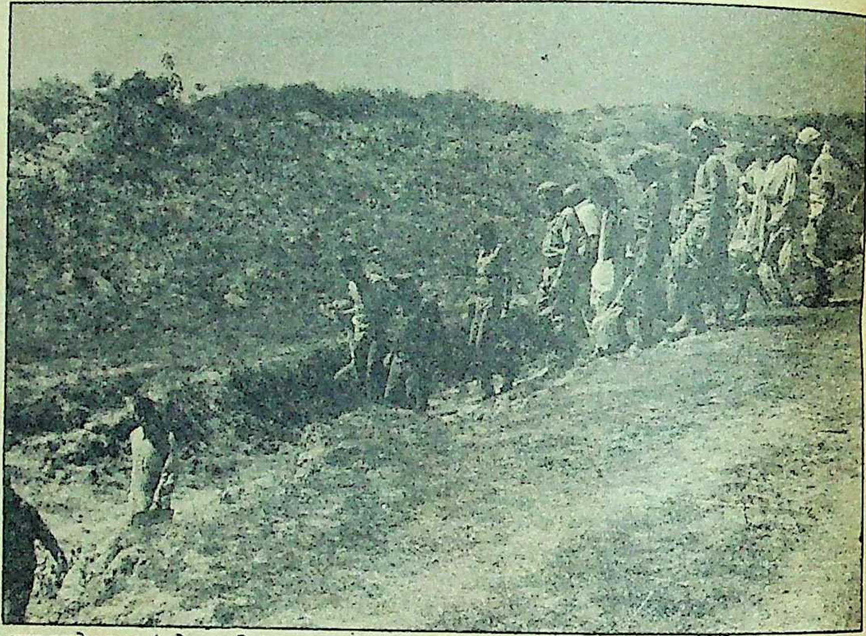

आग लगने पर कुआं खोदना : विवादास्पद जमीन का जायजा लेते सरकारी अफसर व पुलिस

प्रायः हर वर्ष मार्च के महीने में जब चने और गेहूं की सुनहरी फसल पककर तैयार हो जाती है, तो गंगा के इस पार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हांसनगर और गंगा के उस पार बिहार के भोजपुर जिले के नैनीजोर गांव के निवासी अपने-अपने हथियार संभाल लेते हैं और फसल कटने के विवाद में अकसर रक्तपात होता है। पिछले सौ वर्षों से यह सिलसिला जारी है, लेकिन इस वर्ष तो इस विवाद में दोनों प्रदेशों के अर्धसैनिक बलों ने भी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे संभाल लिये हैं। देश के दो प्रांतों के बीच यह विवाद दो देशों के बीच सीमा विवाद जैसा रूप क्यों लिये हुए है? विकास झा द्वारा छानबीन :

बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित दियारे की जमीन को लेकर दोनों प्रांतों के बीच का वर्षों पुराना घाव अब फिर हरा हो गया है। यों, इस विवाद को लेकर अमूमन प्रतिवर्ष दोनों प्रांतों के किसानों में हिंसक झड़पें होती रही हैं। पर इस वर्ष मार्च के दूसरे सप्ताह से यहां जिस किस्म का हिंसक टकराव चल रहा है, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ था। तकरीबन सात हजार एकड़ में लगी रबी की फसल की कटाई के प्रश्न पर बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित नैनीजोर दियारा इन दिनों फिर भयावह रूप से दहक रहा है। दरअसल, बिहार के किसानों को इस बात का गुस्सा है कि प्रति वर्ष फसल वे लोग बोते हैं और जब फसल काटने का समय आता है, तो उत्तर प्रदेश के किसान पीएसी की पलटन समेत आ धमकते हैं और फसल काटकर चल देते हैं। बिहार के किसानों का आक्रोश है कि अब वे सब इस स्थिति को और नहीं झेलेंगे। इसलिए मार्च महीने में भी जब उत्तर प्रदेश के हांसनगर के किसान पीएसी की मदद से नैनीजोर में फसल काटने घुसे, तो बिहार के किसान भी आपा खो बैठे। बिहार के किसानों द्वारा सख्त प्रतिरोध किये जाने से उत्तर प्रदेश के किसान भी उत्तेजित हो गये। नतीजतन, दिनों-दिन स्थिति बिगड़ती ही चली गयी। अपने उग्र किसानों को नियंत्रित रखने के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाद स्थल के निकट पीएसी की कंपनियां तैनात कर दीं, तो वहीं बिहार सरकार की तरफ से भी अपने उत्तेजित किसानों को शांत रखने के लिए पुलिस की भारी भरकम व्यवस्था की गयी। पर बिहार के किसानों का कहना है कि पीएसीवाले दहशत फैलाने के लिए बढ़-चढ़कर आये-दिन फायरिंग कर रहे हैं, ताकि बिहार के किसान आखिरकार अपना दावा छोड़कर भाग खड़े हों। तनाव का जायजा लेने के लिए जब बिहार के शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी केबी कुंवर १८ मार्च को घटनास्थल पर गये, तो पीएसी की तरफ से फायरिंग हो रही थी। केबी कुंवर के वाहन के ठीक बगल से गोली सरसराती हुई निकल गयी और संयोग से कुंवर आहत होने से बाल-बाल बच गये। बिहार के किसानो का कहना है कि पीएसी के इस आक्रामक रुख से जब बिहार के आला पुलिस अधिकारी बाल-बाल बच रहे हैं, तो आम लोगों की भला क्या बिसात। दूसरी तरफ पीएसीवालों का कहना है कि वे कहीं से भी आक्रामक नहीं हो रहे हैं। वे सब बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बहरहाल, दोनों प्रांतों की इस तबाह सीमा पर दोनों प्रांतों की पुलिस पोजीशन लिये बैठी है, मानो यह एक देश के दो प्रांतों की बात नहीं, बल्कि दो दुश्मन देशों के बीच युद्ध का मौका हो।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हांसनगर के किसानों और बिहार के भोजपुर के नैनीजोर के किसानों के बीच जारी इस स्थायी झगड़े का मूल कारण गंगा की बदलती धारा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की बहुत सी जमीन बिहार में और बिहार की बहुत सी जमीन उत्तर प्रदेश में आती-जाती रहती है। गंगा के कटाव की वजह से जब

उत्तर प्रदेश के किसान अपनी दावेदारी के संग उस जमीन पर पहुंचते हैं, तो बिहार के किसानों को आपत्ति होती रही है, वहीं बिहार के किसानों की बहुत सी जमीन जब उत्तर प्रदेश की सीमा में कटाव के कारण चली जाती है और बिहार के किसान जब अपनी उस जमीन पर स्वाभाविक हक जताने पहुंचते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसानों से उनका टकराव होता है। बिहार के किसानों का कहना है, "बिहार की तरफ से टकराव की कोई बात नहीं। हां, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उनके जायज हक को वर्षों से उलझा रखा है।"

विवाद स्थल : हांसनगर गंगा के किनारे बसा बलिया जिले का एक छोटा सा गाव है। इस गांव के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से तकरीबन ५४ किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम कोने में बक्सर-कोईलवर तटबंध के नीचे बसे गांव नैनीजोर के बाशिंदे भी कृषि पर ही आश्रित हैं। इस गांव की अधिकांश भूमि दियारे में है। इसलिए जमीन ही इन दोनों गांवों के किसानों की जान है।

मार्च के पहले सप्ताह में जब हांसनगर के किसानों ने नैनीजोर के किसानों की जमीन पर लगी फसल काटने की पहल की, तो नैनीजोर के किसानों ने प्रतिरोध किया। नतीजतन, हांसनगर के किसानों की तरफदारी में पीएसी ने १२ मार्च को ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की इस घटना के बाद भोज़पुर व बलिया के जिलाधिकारियों ने आपसी वार्ता से तनाव को निपटाने का निर्णय किया। १४ मार्च को बलिया व भोजपुर के जिलाधिकारियों के बीच बातचीत हुई। इस वार्ता में यह तय हुआ कि अगले ही दिन यानी १५ मार्च से बिहार व उत्तर प्रदेश के अधिकारी संयुक्त रूप से पता लगायेंगे कि किस भूखंड का असली स्वामी कौन है और किसने फसल लगायी है। तय हुआ कि इस निरीक्षण के बाद खेत के असली मालिक को निष्कंटक अपनी फसल काटने में दोनों प्रांतों का प्रशासन मदद करेगा। पर १५ मार्च को जब खेतों की असली मिल्कीयत का जायजा लेने बिहार से भोजपुर के अधिकारी निर्धारित समय पर पहुंचे, तो पाया कि बलिया के अधिकारी लापता हैं। १६ मार्च को फिर वही तांडव शुरू था, जब हांसनगर के किसान पीएसी की मदद से एकबारगी फसल को काटने के लिए टूट पड़े। नैनीजोर के लोगों ने फिर आपत्ति की, तो पीएसी की तरफ से फिर फायरिंग शुरू कर दी गयी। इस फायरिंग में नैनीजोर के किशुन तिवारी घायल हो गये। आठ वर्ष पूर्व २६ मार्च, १९८१ को भी फसल कटाई के संघर्ष में हांसनगर के लोगों ने नैनीजोर के एक लड़के सुभाष को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बहरहाल, १६ मार्च की फायरिंग में घायल किशुन तिवारी ने भोजपुर के ब्रह्मपुर थाने में धारा १४७, १४८, १४९, ३०७ तथा ३२७ के तहत हांसनगर के सुरंजन राय, तारकेश्वर राय, चंद्रिका राय तथा छोटक राय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी। इसी तरह शाहपुर थाने के सारणपुर मौजे के किसान भी बलिया के जगदीशपुर गांव के सशस्त्र जत्थे द्वारा घायल किये गये। शाहपुर थाने में इस घटना की भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। नैनीजोर थाना के प्रभारी उप निरीक्षक नवल प्रभात तिग्गा 'माया' से कहते हैं, "१६ मार्च की फायरिंग के बाद १८ मार्च को शाहाबाद रेंज के डीआईजी केबी कुंवर की जीप बक्सर—कोईलवर तटबंध पर पहुंची ही थी कि पीएसी द्वारा चलाई गोली उनकी जीप से सटकर गुजर गयी।" दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना कि यह गोली नैनीजोर के ही एक व्यक्ति ने चलायी थी।

पृष्ठभूमि : बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर गहराया यह विवाद हाल के वर्षों में उठा हो, ऐसी बात नहीं। दरअसल, नैनीजोर के किसान दावा कर रहे हैं कि १८४० से ही उनके पूर्वज दियारे की इस जमीन पर खेती करते रहे हैं। पहले डुमरांव के राजा की जमींदारी में यह जमीन थी और नैनीजोर के किसान डुमरांव राजा को मालगुजारी भी देते थे। इस जमीन पर रैयती अधिकार भी डुमरांव के राजा ने ही नैनीजोर के लोगों को दिया था। पर गंगा की धारा में निरंतर परिवर्तन ने विवाद खड़ा कर दिया और नैनीजोर के किसानों की जमीन पर हांसनगर के किसान दावा ठोंकने लगे।

ब्रिटिश शासनकाल में जब यह विवाद उठा

मस्ती का
नाम है मस्ताबा

मस्ताबा
टू इन वन

1.5 ग्राम, 3 ग्राम तथा 5 ग्राम के पाउच में उपलब्ध हैं।

BUSS/DEL

मार्केटिंग एजेंट:
धर्मपाल सत्यपाल
ए-50, सैक्टर, 4, नौएडा, गाजियाबाद (यू०पी०)

वैधानिक चेतावनी—तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

था, तो १८७१ में अंग्रेज अधिकारियों ने समस्या के निदान के लिए जो रास्ता निकाला, उसने आगे विवाद को और तीव्र ही किया। दरअसल, अंग्रेज अधिकारियो ने १८७१ में बाकायदा एक अधिनियम बनाकर भोजपुर और बलिया क्षेत्र के बीच बहनेवाली गंगा नदी की मध्य धारा को सीमा रेखा मान लिया था। पर कटाव की वजह से नदी की धारा का रुख जब बदलता था, तो काफी जमीन इधर-उधर हो जाती थी। यानी जितनी बार कटाव होता था, तो गंगा की धारा में परिवर्तन आता था और अंग्रेजों द्वारा निर्धारित सीमा रेखा का भी स्थानांतरण होता रहता था।

बहरहाल, आजादी के कुछ वर्षों बाद जब गंगा की बदलती धाराओं से उत्पन्न भोजपुर व बलिया जिले के बीच के इस विवाद के स्थायी निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश व बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों संपूर्णानंद और डा० श्रीकृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लगातार अनुरोध किया, तो १९६२ में पंडित नेहरू ने 'त्रिवेदी आयोग' का गठन कर दिया। त्रिवेदी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट १९६४ में दे दी और संसद ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर १९६८ में एक अधिनियम पारित किया जो बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम १९६८ कहलाता है। इस अधिनियम के अनुसार बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच जमीनों का हस्तांतरण हुआ। अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि जमीनों के हस्तांतरण का प्रभाव किसानों के रैयती अधिकारों पर नहीं पड़ेगा। दोनों प्रांतों की सरकारें एक दूसरे को भू-अभिलेखों का हस्तांतरण करेंगी और उसी भू-अभिलेख को आधार मानकर भू-अभिलेख लेनेवाली सरकार संबंधित किसानों को रैयती अधिकार संबंधी कागजात देगी। इस अधिनियम के ही अनुसार नैनीजोर के किसानों की करीब ५००० एकड़ जमीन १९७० में बिहार से उत्तर प्रदेश में विधिवत हस्तांतरित कर दी गयी। जमीन हस्तांतरण के समय ही बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित जमीन संबंधी संपूर्ण अभिलेख सौंप दिये। अधिनियम के अनुसार हस्तांतरित जमीन पर उसी किसान का कब्जा रहना था, जिसके संबंध में हस्तांतरण करनेवाली सरकार भू-अभिलेख दूसरे सरकार को दे चुकी थी। अधिनियम के अनुसार नैनीजोर के उन किसानों का रैयती अधिकार उन जमीनों पर बने रहना था, जिसे बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किया था। पर उत्तर प्रदेश शासन ने नैनीजोर के किसानों को कभी रैयती अधिकार संबंधी कोई कागज नहीं दिया। जबकि १९७१ में बिहार सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के भूस्वामियों की बिहार में पड़नेवाली जमीन पर कब्जा भी दिलवाया गया और उन जमीनों की मालगुजारी की रसीद भी बिहार में कटने लगी।

आरक्षी उपाधीक्षक गिरिधारीलाल

> **बलिया के आरक्षी उपाधीक्षक गिरिधारी लाल इस बात से इनकार करते हैं कि पीएसी ने नैनीजोर के किसानों पर हमले की नीयत से फायरिंग की। वे कहते हैं कि पीएसी के जवानों ने सिर्फ आत्मरक्षार्थ गोलियां चलायीं।**

विवाद का आरंभ तब हुआ, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहना शुरू किया कि नैनीजोर के किसानों की कोई जमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आयी है। लिहाजा, नैनीजोर के किसान हतप्रभ रह गये। उनके द्वारा दायर एक याचिका पर पटना उच्चन्यायालय ने भारत सरकार तथा बिहार व उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि नैनीजोर की समस्या का शीघ्र निदान निकाला जाये। पटना उच्चन्यायालय का यह निर्णय २८ फरवरी, १९८३ को हुआ। इस निर्णय के बाद ही १९ अक्तूबर, १९८४ को दिल्ली में गृहमंत्रालय के तत्वावधान में बिहार व उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की बैठक हुई और तय हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार द्वारा दिये गये भू-अभिलेखों की बात से कभी इनकार नहीं करेगी। हांसनगर के किसान इस निर्णय को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुए और हांसनगर के रामबदन राय ने इलाहाबाद उच्चन्यायालय में एक याचिका दायर की। इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने २५ फरवरी, १९८८ को उस याचिका को रद्द करते हुए कहा कि दिल्ली में दोनों प्रांतों के अधिकारियों की बैठक में लिये गये फैसले को ही बरकरार रखा जाये। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह कागजी सबूत और साक्ष्य देखकर किसानों को रैयती अधिकार संबंधी परचा दे दे। लिहाजा, नैनीजोर के किसान इलाहाबाद उच्चन्यायालय के उस निर्देश की प्रति सहित अपना आवेदन लेकर बलिया के जिलाधिकारी के पास गये कि अब तो सरकार सबूत व साक्ष्य देखकर उनके साथ न्याय कर दे। पर बलिया के जिलाधिकारी उनकी बातें अनसुनी करते रहे। नैनीजोर गांव के गोविंद तिवारी 'माया' से कहते हैं, "जब बीज बोने का समय आता है, तो हांसनगर के किसान सोये रहते हैं और हम बीज बोते हैं। हां, फसल कटाई के समय वे हथियारों से लैस होकर दावा करने पहुंच जाते हैं।" नैनीजोर के लोगों का कहना है कि इस तनाव में अब तक अनगिनत जानें जा चुकी हैं। नैनीजोर के किसानों पर बलिया में बेहिसाब झूठे मुकदमे दर्ज हैं, ताकि नैनीजोर के किसान सदैव भयभीत रहें। बक्सर के दबंग आरक्षी उपाधीक्षक शशिनाथ झा 'माया' से कहते हैं कि पीएसी ने पिछले दिनों जो कुछ हरकत की, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बलिया के आरक्षी उपाधीक्षक गिरिधारी लाल इस बात से इनकार करते हैं कि पीएसी ने नैनीजोर के किसानों पर हमले की नीयत से फायरिंग की। वे कहते हैं कि पीएसी के जवानों ने सिर्फ आत्मरक्षार्थ गोलियां चलायीं।

बहरहाल, अगर त्रिवेदी आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया होता, तो यह विवाद बहुत पहले खतम हो गया होता। सिन्हा घाट से बक्सर तक त्रिवेदी आयोग ने सीमा निर्धारण के लिए खंभे भी गड़वाये थे, पर असामाजिक तत्वों ने उन खंभों को भी उखाड़ कर गायब करवा दिया।

सीमा विवाद के निदान के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह में बिहार सरकार के भूमि सुधार आयुक्त आरसी अरोड़ा दिल्ली में तय एक बैठक में शरीक होने गये। २० मार्च को पटना के आयुक्त निशिकांत सिन्हा और बनारस के आयुक्त राजीव शाह के बीच इस मसले पर लंबी बातचीत हुई और तय किया गया कि जिस किसान के बारे में इस बात की सही पुष्टि हो जायेगी कि वही अमुक भूखंड का मालिक है और उसी ने उस खेत में फसल बोयी है, तो उस किसान को पुलिस संरक्षण सुलभ करवाकर फसल काटने में मदद की जायेगी। जिस भूखंड पर ज्यादा विवाद होगा और किसी के स्वामित्व की पुष्टि नहीं होगी, उस जमीन की फसल जब्त कर बलिया की कार्यपालक अदालत में फैसले के लिए मामला सौंपा जायेगा। यह भी तय हुआ कि हांसनगर व नैनीजोर के किसानों को अपने हथियार तत्काल समर्पित करने होंगे। पीएसी को हिदायत दी गयी कि वह बेवजह गोलीचालन बंद करे। इस संबंध में ४ अप्रैल को दिल्ली में दोनों प्रांतों के राजस्व मंत्रियों की बातचीत हुई। ३० जून तक मामले को निपटाये जाने का निर्णय लिया गया है। देखना है, यह मामला निपट पाता भी है या नहीं। अगर गुजरे वर्षों की तरह इस बार भी बिहार-उत्तर प्रदेश के अधिकारी सुस्त पड़ गये, तो तय है कि नैनीजोर में हिंसक संघर्ष का सिलसिला बढ़ता ही जायेगा।

—विकास कुमार झा/प्रशांत

छाया: दीपक कुमार

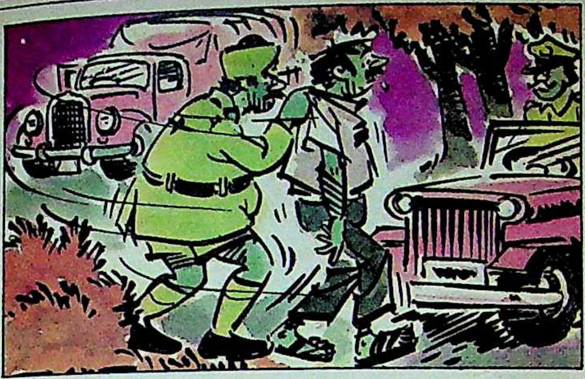

चलो साहब के पास !

नकली परिवहन अधिकारी बनकर कोई पैसा वसूले या कोई शोहदा कोई गलत काम करे, तो ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जब पुलिस स्वयं लूटने लगे, तो बेचारा लुटनेवाला किससे गुहार करे? पिछले दिनों बलिया जिले के नरही थाना अंतर्गत भरौली गोलाम्बर पर गस्त करनेवाले सिपाहियों ने ट्रकों से रुपए उगाहने का कुछ ऐसा ही नायाब तरीका खोज निकाला था।

बताया जाता है कि थाने के जिन दो सिपाहियों की ड्यूटी उपर्युक्त चौराहे पर लगी थी, उनमें से एक सिपाही बलिया से उजियार घाट मार्ग पर चलनेवाली जीप को खड़ी कर उस पर बैठ जाया करता था। जब ट्रकें उधर से गुजरतीं, तो दूसरा सिपाही हर ट्रक को रोककर मनमाने रुपए वसूल करता। यदि कोई ड्राइवर रुपए देने में आनाकानी करता, तो वह ड्राइवर पर धौंस जमाते हुए कहता कि चलो 'बड़े साहब' बुला रहे हैं। बड़े साहब का नाम सुनकर ड्राइवरों की घिग्घी बंध जाती और वे डरते-कांपते 'बड़े साहब' बने जीप पर बैठे सिपाही के पास खिंचे चले आते। बड़ा साहब बना सिपाही ड्राइवर पर बरसता और ड्राइवर अपना पिंड छुड़ाने के लिए अपनी जेब ढीली कर देता। इसके बाद दोनों सिपाही बंटवारा कर लेते। उनका यह धंधा काफी समय तक फलाफूला।

दूल्हा वही जो डकैतों को भाये

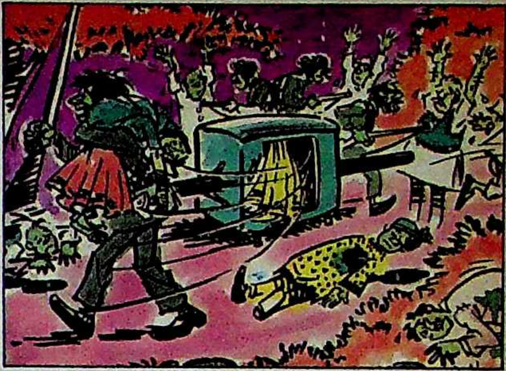

हिंदी में मसालेवाली ऐसी कितनी ही फिल्में बनी हैं, जिनमें अपनी प्रेमिकाओं को पाने के लिए नायकों ने डाकुओं की मदद ली है। लेकिन अब लगता है कि वास्तविक जीवन में प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए डाकुओं की मदद लेने लगे हैं।

हाल ही बिहार के अघौरा क्षेत्र के भगोपुर गांव में गयी बारात के साथ कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें डकैत दुल्हन को तो उठा ही ले गये, बारातियों को भी मौत के घाट उतार दिया।

इस जानी-बूझी डकैती के पीछे कहानी कुछ यों है। दरअसल दुल्हन बनी गीता का प्रेम उसी के गांव के एक युवक से था, लेकिन उसके मां-बाप उसके प्रेम-संबंधों का विरोध करते थे। इसीलिए उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। गीता के प्रेमी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। वह मौके की तलाश में था और गीता को किसी प्रकार हासिल करना चाहता था। उसके लिए उसने डकैतों की शरण ली।

इधर विवाहोपरांत जब गीता विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी, तो अघौरा जंगल के पास डकैतों ने बारात को चारों ओर से घेर लिया और बिना कुछ कहे दूल्हे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दुल्हन को डोली से खींचकर बाहर किया और जंगल की ओर निकल गये। जाते समय वे तीन अन्य बारातियों को भी गोली मारते गये। गीता का मिलन उसके प्रेमी से हुआ या वह डकैतों के गिरोह में फंस गयी, राम जाने।

आठ हजार का चुंबन

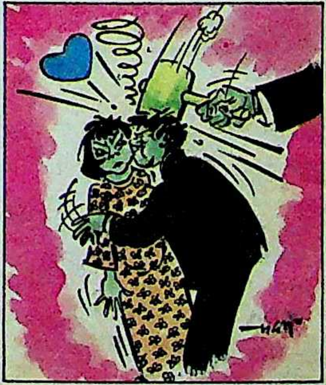

किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री का उसकी मर्जी से चुबंन लेना गुनाह नहीं, लेकिन यदि कोई पुरुष जबरदस्ती किसी स्त्री को चूम ले, तो कतई गुनाह है। कुछ ऐसा ही गुनाह सिंगापुर गये भारतीय पर्यटक दो बच्चों के बाप, लेकिन विधुर अमरजीत से हो गया, परिणाम-स्वरूप जिला जज ने उस पर एक हजार सिंगापुरी डालर यानी आठ हजार रुपए जुर्माना ठोंक दिया।

२७ वर्षीय अमरजीत ने बताया कि नये साल की खुशी में वह कुछ ज्यादा ही उमंग में था। रेस्तरां की एक जापानी परिचारिका पर उसका ऐसा दिल आ गया कि उसके साथ वह फोटो खिंचवाने के लिए मचल उठा। वह फोटो खिंचवाने के लिए तैयार भी हो गयी, लेकिन जापानी रमणी का संस्पर्श उसको इतना उद्दीप्त कर बैठा कि अमरजीत जरूरत से ज्यादा लिफ्ट ले बैठा। आव देखा न ताव, उसने जापानी युवती को चूम लिया। बस फिर क्या था, युवती ने शिकायत की और अमरजीत को चुंबन की कीमत हजारों में चुकानी पड़ गयी।

पुलिस जो न करे !

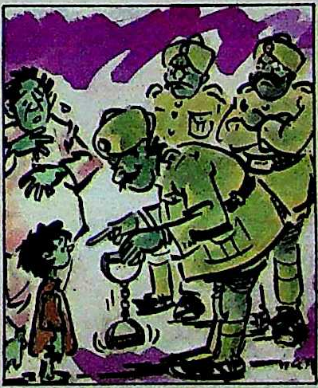

हजार-पांच सौ रुपए लेकर किसी को भी किसी केस में फंसा देना पुलिस के लिए आम बात होती है, लेकिन कभी-कभी वह चालाकी दिखाने में भी ऐसी चूक कर जाती है कि खुद अपने बनाये जाल में फंस जाती है। मथुरा जिले की छाता पुलिस एक पांच वर्षीय अबोध बालक को बलवे, मारपीट और जान से मार देने की धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर खुद पसोपेश में पड़ गयी है।

छाता पुलिस पथौली निवासी रामसिंह के पांच वर्षीय बेटे मदन पर धारा १४७, ३२३ और ५०६ के तहत मुकदमा दर्ज कर जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची और मदन के हाथों में हथकड़ी डाली, तो उसके नन्हे-नन्हे हाथों से हथकड़ी फिसलकर बाहर निकल गयी। पहले तो पुलिस ने मदन के पिता से कहा कि जमानत कराने की कोई जरूरत नहीं, पर बाद में कहा कि जमानत कराना जरूरी है। अब पुलिस की माया तो वही जाने।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

रूप का व्यवसाय : पामेला बोर्डेस

पामेला सेक्स प्रकरण

जब 'मिस इंडिया' कालगर्ल बनी !

रूप के शालीन प्रदर्शन से वह ख्यात हुई थी, लेकिन रूप के व्यवसायीकरण ने उसे कुख्यात कर दिया। आखिर क्या कारण था कि पामेला भारत सुंदरी से विश्व की सबसे महंगी कालगर्ल बन गयी ? ब्रिटेन में क्रिस्टीन कीलर के बाद सर्वाधिक चर्चित सेक्स प्रकरण की अंतर्कथा :

“भारतीय मूल के दो शख्सों ने ब्रिटेनवासियों की नींद हराम कर रखी है।” ऊपर से यह उक्ति किसी अखबार की सुर्खी लग सकती है, लेकिन दरअसल है यह एक हकीकत, जो न केवल हर ब्रिटेनवासी की जबान पर छा गयी है, बल्कि जिससे ब्रिटेन की सरकार, सत्तारूढ दल और पूरा सभ्य समाज स्तब्ध है। बंबई में जन्मे सलमान रुश्दी ने अपने उपन्यास 'सेटेनिक वर्सेज' से ब्रिटेन में आर्थिक-राजनीतिक बवंडर तो ला ही दिया था, अब बंबई की विख्यात सुंदरी पामेला सिंह बोर्डेस ने वहां सत्ता के गलियारे तक अपना जाल बिछाकर तख्ता-पलट तक का रास्ता दिखा दिया है।

अभी दो सप्ताह पूर्व ही लंदन में क्रिस्टीन कीलर-प्रोफ्यूमो प्रसंग को लेकर बनी फिल्म 'स्कैंडल' का प्रीमियर शो हुआ था। इसे देखने के बाद हर किसी ने गहरी सांस छोड़कर, इसे बीता इतिहास करार देते हुए इच्छा प्रकट की थी कि ऐसे कांड की आवृत्ति न हो। संभवतः तब तक ब्रिटेन के लोग इस सच से बेखबर थे कि इसी समय एक और 'सेक्स-स्कैंडल' ज्वालामुखी बन गया है जो फटते ही 'कीलर-कांड' को भी मात कर देनेवाला है। पिछले वर्ष अमरीकी राष्ट्रपति पद के तगड़े डेमोक्रेटिक उम्मीदवार गैरी हार्ट द्वारा 'सेक्स कांड' के कारण मौका खोने के बाद, यह प्रमुख 'सेक्स कांड' है जिसकी प्रतिध्वनियां दुनिया भर में विशेषकर भारत में सुनायी दे रही हैं।

अखबारी सुर्खी : इस कांड के गरमाते ही गत कुछ सप्ताहों से लंदन के अखबारों में यह आलम है कि लगभग हर दिन प्रथम पृष्ठ पर किसी-न-किसी हस्ती के साथ अंतरंग अवस्था में पामेला का चित्र छपता है। पिछले कुछ वर्षों से उसने जिस प्रकार ब्रिटेन के अभिजात वर्ग के लोगों को अपने रूप-जाल में फांसकर पार्टियों और पिकनिकों में साथ घुमाया था और गरमागरम फोटो खिचवाये थे, वे सभी अब छपकर उसकी गवाही दे रहे हैं। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक पामेला वेश्यावृत्ति के अपने धंधे में प्रति रात १००० पौंड वसूलती है। खेलमंत्री कालिन के साथ पामेला की तस्वीर देखकर इस प्रकरण की तह में उतरकर पहली बार इस कांड का रहस्योद्घाटन करनेवाले 'न्यूज आफ दि वर्ल्ड' के पत्रकार के साथ भी पामेला रात बिताने को तैयार हो गयी, केवल ५०० पौंड (रियायती दर) पर। इस पत्रकार ने कई सप्ताह की मेहनत के बाद पूरी रपट ज्यों ही प्रकाशित की, हर ओर तहलका मच गया। कई पत्रकार पामेला की पिछली जिंदगी में झांकने के लिए बंबई, दिल्ली, जयपुर पहुंच गये। बंबई से प्रकाशित 'फेमिना' पत्रिका के कार्यालय में तो लंदन से टेलीफोनों का तांता ही लगा रहा।

'संडे स्पोर्ट' अखबार के मालिक डेविड सुलिवान का कहना है कि वे शीघ्र ही पामेला के कुछ 'नग्न चित्र और विशेष सामग्री' प्रकाशित करनेवाले हैं। पामेला की 'प्रसिद्धि' भुनानेवालों की भी कमी नहीं है। पुरुषों की पत्रिका 'मेन्स ओनली' के संपादक नेविल प्लेयर ने पामेला को एक नग्न चित्र देने के लिए ८५ हजार पौंड का प्रस्ताव रखा है। यह किसी भी नग्न चित्र के लिए पेश की गयी सबसे बड़ी राशि है।

विवादास्पद पृष्ठभूमि : 'भारत सुंदरी' का खिताब पाने के पूर्व पामेला सिंह एक ऐसी विवादास्पद लड़की रही है जिसका घरेलू जीवन संतोषप्रद नहीं था। इसी कारण पामेला अपने जीवन की पृष्ठभूमि को छिपाती भी रही है। वह एक परंपरागत आचार-विचार वाले ऐसे फौजी परिवार की लड़की है जिसके तीन सदस्य देश के लिए लड़ाई में मारे गये हैं। जब वह दो साल की थी तभी उसके

पिता, मेजर महिंदर सिंह चौधरी १९६२ के भारत-चीन युद्ध में शहीद हो गये। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। पामेला की स्कूली शिक्षा शिमला में शुरू हुई और जयपुर में आकर पूरी हुई। शिमला में पामेला और उसका भाई (जो उससे दो साल आगे था) एक साथ छात्रावास में रहते थे और स्कूल में पढ़ते थे। उनके पास खर्चे की तंगी रहा करती थी। इस तंगी को नामंजूर कर, पामेला की मां शकुंतला चौधरी, जो दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी हैं, बताती हैं कि पामेला को अच्छी शिक्षा देने की सारी व्यवस्था की गयी, "वह अपनी कक्षा में सदा प्रथम आती थी और घुड़सवारी, तैराकी, नृत्य तथा टेनिस में भी औकात से अधिक कमाल दिखाती था।"

दक्षिण दिल्ली में पामेला के मां-बाप का अपना घर है। संदेह व्यक्त किया जाता रहा है कि यह मकान पामेला के देह-व्यापार से अर्जित धन से ही खरीदा गया था। शकुंतला चौधरी इस बात को 'गलत और गंदा आक्षेप' करार देती हुई कहती हैं; "यह घर, जहां मैं रहती हूं, पामेला के जन्म से पहले ही खरीदा गया था।"

जयपुर स्थित महारानी गायत्री देवी स्कूल में पामेला १९७६ से १९७९ तक पढ़ती रही। वहां की सहेलियों और परिचितों के अनुसार वह छात्रावास में रहती थी और 'मेरिट स्कालर शिप' (छात्रवृत्ति) पाती थी। छात्रवृत्ति की ही रकम से उसे अपने सारे काम चलाने पड़ते थे। उसके पिता तो गुजर ही चुके थे, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन की कर्मचारी उसकी मां भी न कभी उससे मिलने आती थी और न चिट्ठी लिखती थी, हालांकि पामेला अकसर पत्र लिखा करती और परेशान रहती थी। उसके पास एक ही व्यक्ति आता था. जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक गतिविधि वाला आदमी था। वह स्वयं को पामेला का अभिभावक भी बताता था। स्कूल में पामेला एक धावक थी। वह कक्षा-प्रतिनिधि भी थी और खुशमिजाजी की बदौलत लड़कियों को बहुत प्रिय थी। साथ की छात्राएं उसे 'पाम जीजा' कहा करती थीं। सहपाठिनी अंजला को खूब याद है, "उसने एक गिलहरी पाल रखी थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। जब वह कक्षा को 'मार्च पास' करती थी तब भी उस गिलहरी को अपनी 'चुन्नी' पर बिठा लेती थी।" एक सहपाठिनी (जिसके घर पामेला जाया करती थी) की मां बताती हैं, "उसके जीवन में कोई न कोई दुखद और करुणाजनक बात जरूर थी। संभव है, उसके जीवन की पृष्ठभूमि खुशहाल न हो या परिवार में उसे अपेक्षित प्यार-दुलार और संतोष न मिला हो।"

जयपुर में पामेला एक साधारण-सी दिखनेवाली लड़की थी, बहुत कम लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता था। इसी कारण १९८२ में जब वह 'भारत सुंदरी' घोषित की गयी, तो उसे करीब से जाननेवालों को आश्चर्य हुआ। जिस छात्रावास में पामेला रहती थी, उसकी वार्डन रह चुकी एक महिला का कहना है कि 'मेरिट स्कालरशिप' की राशि पर ही निर्भर होने के कारण वह अकसर हीनता का अनुभव करती थी, "संभव है, अर्थाभाव और मां द्वारा घोर उपेक्षा ने ही उस होनहार लड़की को कुमार्ग पर ठेल दिया हो।"

दिल्ली की देन: शकुंतला चौधरी सहित, पामेला से परिचित लोगों के मुताबिक, "यह प्रतिभाशाली लड़की दिल्ली आने के बाद ही बिगड़ी और ऐसा दिल्ली में पढ़नेवाली अधिकतर लड़कियों के साथ होता है। राजधानी में पामेला का दाखिला दक्षिण दिल्ली स्थित एक पालीटेकनिक में टेक्सटाइल डिजाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में हुआ। यहीं से प्रसिद्धि पाने और चोटी के लोगों से हेलमेल बढ़ाने की दिशा में उसकी कोशिशें शुरू हुईं। जब वह दिल्ली के ही एक कालेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा बनी, तभी मार्डलिंग के धंधे से जुड़ गयी।

उसे जाननेवाले लोग बताते हैं कि पामेला बेहद 'लूज कैरेक्टर' (ढीले चरित्र) की लड़की थी। अपनी मां से उसके संबंध तब बिगड़े जब वह पढ़ाई-लिखाई से मन हटाकर मार्डलिंग के अपने धंधे की कमाई से विलासपूर्ण जीवन जीने लगी। उसकी बेशर्म हरकतें उसके रूढ़िवादी परिवार को नागवार गुजरने लगीं। शकुंतला चौधरी कहती हैं, "एक बार तो उसके रात-रात भर की आवारागर्दी और

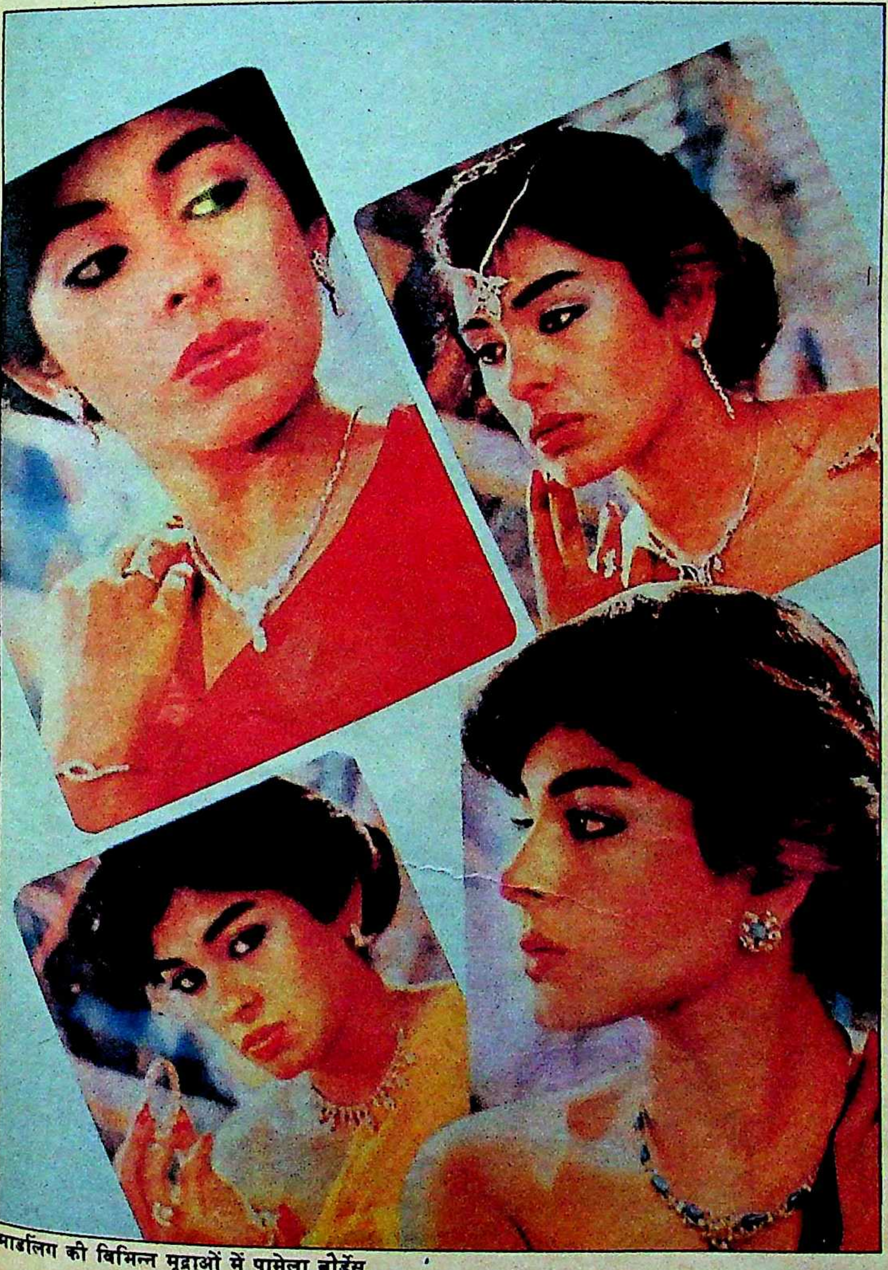

मार्डलिंग की विभिन्न मुद्राओं में पामेला बोर्डेस

निर्लज्ज व्यवहार के कारण मैंने 'चेन' (सिकड़ी) से उसकी पिटाई कर दी।" कालेज और छात्रावास के अधिकारियों ने जब कड़ी चेतावनी दी तब पामेला ने पढ़ाई ही बंद कर दी। बाद में वह बंबई चली गयी।

शिमला में पामेला के स्कूली दोस्त रह चुके एक व्यक्ति के अनुसार जब वह दिल्ली के कालेज में पढ़ती थी, तब दक्षिण दिल्ली के एक खतरनाक होटल में अकसर दिखायी पड़ती थी। वह व्यक्ति १९८१ में दिल्ली आया था। उसने पता लगाकर पाया कि पामेला उस होटल में 'कालगर्ल' का काम कर रही है। इस आदमी का कहना है, "उन दिनों पामेला ऊंचे तबके के लोगों में जानी जाने लगी थी और मेरा खयाल है कि अपने कालेज की अन्य लड़कियों के साथ वह होटल में मजा लेने के ही लिए जाती थी, पैसे के लिए नहीं।"

ख्वाहिश की राह: बहरहाल, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के प्रशिक्षण से अलग हो उसने टाइम्स आफ इंडिया समूह की पत्रिका 'फेमिना' द्वारा आयोजित 'मिस इंडिया स्पर्धा' में भाग लिया (१९८०), लेकिन सफल न हो सकी। पामेला की दिली ख्वाहिश एक सफल माडल बनने की थी। कुछ हद तक वह इस मामले में सफल भी रही। उसने अपने संपर्कों और उन्मुक्त सौंदर्य की बदौलत नैस्कैफे (काफी), ओरके मिल, ताज फोर्ट आगुडा जैसे संस्थानों के विज्ञापन कैंपेन हासिल किये। इन विज्ञापनों की आउटडोर शूटिंग में उनके साथ रहनेवाली आज की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री निशा सिंह उसके बारे में बताती हैं, "वह एक अत्यंत सुंदर तथा उन्मुक्त ख्यालों वाली लड़की थी। वह बहुत अंतर्मुखी भी थी। एक बार जब मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसके माता-पिता अलग हो चुके हैं और वह इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहती।"

कुछ समय तक उसने होटल ओबेराय के ब्यूटी पार्लर 'सिहोर' में भी काम किया था। संपर्क किये जाने पर इस पार्लर की मैनेजर रीता सेठी की प्रतिक्रिया थी, "मुझे तो उसकी याद भी नहीं है। उसने केवल कुछ दिनों ही यहां काम किया।" माडलिंग जगत के प्रमुख फोटोग्राफर जितेंद्र आर्य को पामेला की देह का भूगोल अच्छी तरह याद है, "मैंने उसके कुछ अर्धनग्न और ग्लैमरस फोटो खींचे थे, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उसकी मंजिल सात समुंदर पार, सैलानियों के बिस्तर तक है।" उद्योग की एक अन्य वरिष्ठ माडलर ने नाम न छापने के अनुरोध सहित बताया कि पामेला चरित्र के मामले में तो बहुत ही 'लूज' थी। हर पुरुष माडल (कभी-कभी कतिपय छायाकारों) के साथ वह पायी जाती थी। जो भी हो, बंबई में तीन वर्ष तक छायी रहने के बाद पामेला ने १९८२ में ज्यों ही 'मिस इंडिया' का खिताब जीता, उसे अपने लक्ष्य का रास्ता मिल गया। 'फेमिना' को दिये साक्षात्कार में उसने बताया था कि उसकी दिली इच्छा, न्यूयार्क में माडलिंग करने की और विश्वविख्यात हेयर ड्रेसर हैरी किंग से केशविन्यास के कुछ गुर सीखने की है।

रूप की पहली विजय: 'मिस इंडिया' पामेला

निश्चय ही उसके पास एक अद्भुत कहानी है और बहुत सारे लोग उस कहानी को जानने के लिए उत्सुक हैं। यह कहानी वह अवश्य कहेगी।

'मिस इंडिया' बनने के बाद 'मिस यूनीवर्स' की प्रतियोगिता पेरू के लीमा शहर में होनी थी। भारत से लीमा रवाना होते ही पामेला ने अपने 'लक्ष्य' की ऐसी सीढ़ी चढ़नी शुरू की कि उसकी परिणति आज थैचर सरकार के लिए 'सबसे गंभीर संकट' के रूप में हुई है।

पामेला लीमा से लुप्त होने के पांच वर्ष बाद ब्रिटेन की 'सबसे महंगी कालगर्ल' के रूप में पुनः अखबारों की सुर्खियों में है। अब तक की खबर में कहा गया है कि पामेला दुनिया के सबसे बड़े धनी और हथियारों के डीलर अदनान खशोगी, फिल्मों के हास्य कलाकार जिम डेविडसन, 'संडे टाइम्स' के संपादक एंड्रनील व 'दि आब्जर्वर' के संपादक डोनाल्ड ट्रेलफोर्ड की मित्र व अंकशायिनी बनी है। इन खबरों से इस कांड ने तूल पकड़ा। असली मामला ब्रिटेन के प्रभावशाली खेल मंत्री कालिन मोइनिहान के साथ उसके अत्यंत 'नजदीकी रिश्ते' और सत्तारूढ़ टोरी (कंजर्वेटिव) पार्टी के सांसद डेविड शा की निजी सहायक के रूप में उसकी नौकरी का है। वह शा के साथ ब्रिटिश संसद तक आती थी।

इस कांड की लपटें तेज उठने के कई और भी कारण हैं, जैसे कि थैचर प्रशासन की ढुलमुल विदेश नीति के कारण लोगों में बढता असंतोष, रुश्दी प्रकरण से ब्रिटेन को हुई आर्थिक हानि और सबसे प्रमुख कारण है, २६ वर्ष पहले हुए ठीक इसी तरह के 'कीलर सेक्स कांड' पर पिछले दिनों लंदन में प्रदर्शित विवादास्पद और सफल फिल्म 'स्कैंडल'।

सरोकार और खतरे: तड़क-भड़क का जीवन जीने की दीवानी पामेला ने दुनिया की ऊंची हस्तियों से रहस्यमय नाते जोड़कर जहां ब्रिटिश सिंहासन की स्थिति डांवाडोल कर दी है, वहीं अपनी जान के लिए खतरे भी पैदा कर लिये हैं। वह इंग्लैंड की राजकुमारी एने और उनके पति कैप्टन मार्क फिलिप के साथ भी रह चुकी है। कै० फिलिप उसे घुड़सवारी सिखा रहे थे, उसी दौरान वह एक बार घोड़े से गिरकर घायल भी हो गयी। यह खबर देते हुए 'डेली एक्सप्रेस' (समाचार पत्र) ने बताया कि लीबिया के लोगों से पामेला की जान के लिए फिर खतरे पैदा हो गये हैं। बताया जाता है कि कर्नल गद्दाफी ने एक बार पामेला की मौत का फरमान जारी कर दिया था। पामेला उनके वरिष्ठ सहायक गद्दाफ अल दायन से अकसर मिला करती थी। जब यह भेद खुला तब कर्नल गद्दाफी ने गुस्से में आकर यह फरमान जारी किया था। वह त्रिपोली में दो बार गद्दाफी से भी मिल चुकी थी, इसलिए आशंका की गयी थी कि वह 'यूरोप में लीबियाई कार्रवाइयों का भेद' खोल देगी।

पामेला की गतिविधियों से 'सुरक्षा-भंग' होने के मामले की जांच करनेवाली पुलिस की विशेष शाखा ने संदेह जाहिर किया कि कतिपय अंतरराष्ट्रीय वेश्याओं के साथ सेक्स और ड्रग्स (मादक दवाओं) का धंधा चला रही पामेला ने ब्रिटेन के एक मंत्री सहित १२ संसद-सदस्यों को

फांसा है। इस धंधे में शामिल अधिकतर सुंदरियों के संबंध ऊंची हस्तियों से हैं।

खबरों के अनुसार स्वयंभू भगवान चंद्रास्वामी से भी पामेला के गहरे संबंध रहे हैं। वह चंद्रास्वामी से १९८२ में न्यूयार्क में मिली थी। तब उसने कालगर्ल का कैरियर शुरू ही किया था। वहीं पामेला को एक बिचौलिये ने एक फ्रेंच नागरिक से मिलाया था, जो उससे शादी करना चाहता था। पामेला ने यह शादी कर ली, किंतु मात्र चौबीस घंटों के लिए। पामेला का मकसद, इस शादी के जरिये फ्रांस में प्रवास की अनुमति प्राप्त करना था। दिलचस्प बात यह है कि शादी करानेवाला भी पामेला का दोस्त था और 'ट्रेड विड्स' कंपनी की मार्फत लीबिया, अफगान मुजाहिदीन और ईरान को हथियार सप्लाई करता था।

लंदन से फैली खबरों के अनुसार पामेला बोर्डेस से जुड़ी आशंकाओं की जांच करनेवाली ब्रिटेन की गोपनीय सेवा, 'एमआई ५' ने पामेला को संदेह-मुक्त कर दिया है। अखबारी सुर्खियों के साथ बावेला मचने के बाद पामेला ने 'कामंस सिक्योरिटी पास' (राजकीय सुरक्षा-पत्र) के लिए जो आवेदन पत्र दिया था, उसकी जांच-पड़ताल स्काटलैंड यार्ड (पुलिस) ने की। इस पड़ताल में पामेला से जुड़ी ऐसी कोई बात नहीं पायी गयी, जो उसे संदेहास्पद साबित करे। इसी आधार पर 'एमआई ५' ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पामेला के संबंध आतंकवादी गुटों से या किन्हीं ज्ञात अपराधी गिरोहों अथवा खुफिया संगठनों से हैं। इसके बावजूद समाचार-माध्यमों में नित्य नये विवादास्पद और सनसनीखेज प्रकरण आ रहे हैं। कहते हैं, पामेला ने खुद मंजूर किया है कि अनेक लीबियाई और अरब हस्तियों से उसके दोस्ताना रिश्ते हैं, जबकि ब्रिटिश सुरक्षा सेवाओं के पास उच्चस्तरीय लीबियाई व्यक्तियों से पामेला के संबंधों की कोई सूचना नहीं है। ब्रिटेन की शीर्षस्थ गुप्तचर शाखा 'एमआई ५' ने ही पिछले साल सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के एक सांसद के सेवार्थ एक कामंस रिसर्चर (संसदीय शोधकर्मी) के रूप में काम करने के लिए पामेला को इजाजत दी थी। कामंस स्पीकर बर्नार्ड नीदरील ने इसके लिए 'एमआई ५' को जमकर आड़े हाथों लिया है। आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार का पक्ष यह है कि पामेला से सुरक्षा को खतरा होने के किसी भी साक्ष्य की पूरी जांच और समीक्षा की जायेगी। दूसरी ओर विपक्ष और कुछ सत्तापक्ष के सांसद इस पूरे प्रकरण को ऐसा गंभीर मामला मानते हैं जो पूर्णस्तरीय संसदीय जांच की अपेक्षा रखता है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर पामेला के लीबियाई सरोकार साबित हो गये, तो ब्रिटिश गुप्तचर सेवा के 'प्रशंसनीय रिकार्ड रखने के सारे दावे' काफूर हो जायेंगे और नतीजतन, 'पामेला-कांड' के सुरक्षा संबंधी दुष्परिणामों के सवाल पर मार्गरेट थैचर सरकार को जाना भी पड़ सकता है।

ब्रिटेन के सांसदों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वे सवाल उठाते हैं कि जब इस तरह की गिरी

स्कैंडल पर स्कैंडल

वैसे तो इंग्लैंड में ऐसे कई 'सेक्स कांड' हुए जिनके खुलने से वहां की सरकार तक में कंपकंपी पैदा हो गयी। लेकिन आज से २६ वर्ष पहले वहां हुए उस विश्वप्रसिद्ध 'सेक्स कांड' (स्कैंडल) को भुलाया नहीं जा सकता जिसने ब्रितानी सरकार की चूलें हिलाकर रख दीं। इस पूरे घटनाचक्र का प्रमुख केंद्र थीं—रूप की रानी क्रिस्टीना कीलर। कहते हैं कि मदमाते हुस्न की इस मलिका ने अपने आकर्षण के जाल में तब की तमाम राजनीतिक- व्यावसायिक हस्तियों, अपराध और षड्यंत्र जगत के महारथियों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही नहीं फंसाया, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन की सरकार के युद्धमंत्री जान प्रोफ्यूमो को अपना हमबिस्तर बनाकर ऐसा बावेला खड़ा कर दिया कि कंजर्वेटिव सरकार आम चुनाव में चारों खाने चित हो गयी।

लंदन से ३० किलोमीटर पश्चिम स्थित स्लाग के पास १६ वर्ष तक अवैध संतान के रूप में जीवन बिताने के बाद क्रिस्टीन अपने शबाब को छलकाने १९५८ में लंदन आ बसी। काली व जादूभरी आंखों और लययुक्त देहवल्ली के जादू से उसने शीघ्र ही नगर के एक रात्रि क्लब में 'शो गर्ल' की नौकरी पा ली। यहां उसकी भेंट दूर-दूर तक संबंधों का जाल फैलाकर काम निकालनेवाले घाघ दलाल डा० स्टीफन वार्ड से हुई। वार्ड के मित्रों की सूची में सोवियत राजदूतावास के नौसेना अटैची कैप्टन ह्यूजिन इवानोव भी थे। वार्ड के लिए क्रिस्टीन एक ऐसा मोहरा थी जिसके सहारे वह कई बाजियां जीत सकता था। उसने वही किया। कैप्टन इवानोव के समक्ष क्रिस्टीन कीलर को परोसकर डा० वार्ड ने क्या कुछ हासिल किया या दिया, यह तो अभी तक नहीं जाना जा सका है, परंतु इस सेक्स कांड के खुलते ही ब्रितानिया में राजनीतिक भूकंप आ गया। शीघ्र ही युद्धमंत्री जान प्रोफ्यूमो की कीलर के साथ बितायी गयी रातों का जिक्र भी लोगों की जबान पर आ गया। 'प्रोफ्यूमो-कीलर-इवानोव'—इस रास्ते से गुजरने वाली युद्ध की गुप्त सूचनाओं की अफवाह ने तो आग में घी का काम किया। ब्रिटेन का अभिजात समाज यह कैसे सह सकता था कि एक साम्यवादी व्यक्ति लड़की का सहारा लेकर ब्रिटेन के युद्धमंत्री तक से सूचनाएं प्राप्त कर ले?

खंडन: २२ मार्च, १९६३ को प्रोफ्यूमो ने संसद में इस बात का खंडन किया कि कीलर के साथ उनके कोई संबंध थे। लेकिन प्रतिदिन खुल रहे रहस्यों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हारकर स्वीकार किया कि उन्होंने संसद में झूठ बोला था। ५ जून, १९६३ को प्रोफ्यूमो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाउस आफ लार्ड्स के उपाध्यक्ष वाइकौंत हैलशेम की एक टिप्पणी से तो मैकमिलन की सरकार ही चरमरा गयी। वे इस मामले पर बोले, "निम्न चरित्र की महिलाओं और प्रमाणित झूठों के गठबंधन से रिश्ता रखनेवाली पार्टी को शासन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।"

भले ही न्यायालय में यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि देश की सुरक्षा को इस कांड से खतरा पहुंचा, मैकमिलन की कंजर्वेटिव पार्टी को तो चोट पहुंच ही चुकी थी। १९६४ के आम चुनाव में यह बुरी तरह पराजित हुई।

कांड की परतें खुलते ही कैप्टन इवानोव मास्को भाग गये, जबकि डा० वार्ड पर यह गुनाह सिद्ध हो गया कि वे वेश्या-व्यवसाय से कमाई करते थे। इस जुर्म के लिए उन्हें दंडित किया जाता, इसके पहले ही उन्होंने मादक पदार्थों का ताबड़तोड़ सेवन कर जान दे दी। यह बात दीगर है कि लोग उनकी मौत को अब भी 'अस्वाभाविक' मानते हैं।

गजब तो यह रहा कि इस सारे कांड की नायिका कीलर पर जासूसी का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं किया जा सका और वह आज भी लंदन में एक आलीशान जिंदगी जी रही है। उसने बाद में एक गायक से शादी कर ली।

पिछले दिनों इसी कीलर कांड को लेकर एक फिल्म बनी 'स्कैंडल' जिसके प्रदर्शन ने फिर उस विवाद की याद ताजा कर दी है। इस फिल्म के प्रीमियर पर क्रिस्टीन कीलर विशेष पोशाक पहनकर आयी और उसने दुनिया को जता दिया कि ४७ वर्ष की उम्र में भी वह बिजली गिराने की क्षमता रखती है। ■

हुई औरत सांसद की सहायक बनकर हाउस आफ कामंस तक आ पहुंची है, तब देश की सुरक्षा कैसे सुरक्षित मानी जा सकती है? लंदन के बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि यह इतना गंभीर मामला नहीं है, केवल वह इस प्रसिद्धि को भुनाना चाहती है।

शादी और धंधा: मध्य लंदन के 'वेस्टमिंस्टर' जैसे धनी इलाके में ७५ हजार पौंड की कीमत वाले फ्लैट में रहनेवाली इस 'भारत सुंदरी' का पारिवारिक जीवन तो कलहपूर्ण रहा ही, वैवाहिक जीवन भी सफल न हो सका। बंबई में विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि वह यहीं के एक पंजाबी परिवार में ब्याही थी, जिससे बाद में उसका तलाक हो गया। इसके बाद उसने लंदन में ही एक फ्रांसीसी नागरिक बोर्डेस से शादी की जिसके बारे में कहीं विशेष विवरण सुलभ नहीं है। पिछले ५ वर्षों से लंदन के प्रायः सभी बड़े रेस्तरां, होटलों और पार्टियों में किसी-न-किसी उच्चपदस्थ अधिकारी, संभ्रांत व्यवसायी, फिल्म कलाकार, संपादक या राजनीतिक के साथ उसे देखा जाता रहा है। कुछ वर्ष पहले ही पामेला ने अपनी दूसरी शादी (बोर्डेस के साथ) खतम होने की घोषणा करते हुए, लंदन के एक स्टाक ब्रोकर (शेयर दलाल) के साथ विवाह रचाने का मंशा प्रकट किया था।

१९६३ में हुए 'क्रिस्टीन कीलर सेक्स कांड' और अब के 'पामेला सेक्स कांड' में काफी समानताएं भी हैं। जैसे:

शकुंतला चौधरी कहती हैं, "एक बार तो उसके रात-रात भर की आवारागर्दी और निर्लज्ज व्यवहार के कारण मैंने 'चेन' (सिकड़ी) से उसकी पिटाई कर दी।"

पामेला की मां

० दोनों हीं वारांगनाओं ने अपने-अपने गुल कंजर्वेटिव सरकार के शासनकाल में खिलाये।
० दोनों सरकार के एक-एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री से अपना नाता जोड़े हुई थीं।
० कीलर और पामेला दोनों के अभिभावकों का कोई पता नहीं।
० दोनों उच्च संपर्कों के सहारे वेश्यावृत्ति करती थीं।
० दोनों ने (क्रिस्टीन कीलर ने इंग्लैंड के दूसरे क्षेत्र से और पामेला ने बंबई से आकर) लंदन को ही अपना 'कार्यक्षेत्र' बनाया।
० दोनों के खिलाफ जासूसी या जालसाजी के आरोप साबित नहीं किये जा सके।

अंतिम अध्याय: २० मार्च के 'इंडिपेंडेंट' (समाचार पत्र) के अनुसार पामेला अब अज्ञातवास से एक वकील के साथ बाहर आनेवाली है और अपनी कहानी बतानेवाली है। एक दिन पहले उसने 'मेल' (अखबार) को बताया था कि लीबिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उसके संबंधों का कोई राजनीतिक पहलू नहीं है और ब्रिटिश काबीना के एक मंत्री अपनी काली करतूतें छिपाने के लिए संदेहजनक अफवाहें फैला रहे हैं। अभी तक पामेला बोर्डेस के संबंध खेल मंत्री कालिन मानीहान के साथ ही होने की चर्चा थी, पर समाचार-माध्यमों का कहना है कि ब्रिटिश सरकार में खेलमंत्री से भी अधिक वरिष्ठ कई हस्ती से उसके लफड़े हैं। पामेला का एक मित्र (लंदन में) कहता है, "निश्चय ही उसके पास एक अद्भुत कहानी है और बहुत सारे लोग उस कहानी को जानने के लिए उत्सुक हैं। यह कहानी वह अवश्य कहेगी। वह शोहरत पाने और दौलतमंद बनने की उत्कट अभिलाषा पाले रही है। पहली चीज तो उसने सात दिनों में ही हासिल कर ली। अब उसने दूसरी चीज (दौलत) हासिल करने का इरादा बना लिया है।"

निश्चय ही अपनी बहुआयामी, बहुस्तरीय, बहुरंगी कहानी की बदौलत पामेला अपनी दूसरी हवस पूरी कर लेगी। लेकिन तब तक क्या वह जीवित रह पायेगी? और यह कहानी आम होने पर, ब्रिटेन में उठा तूफान कौन-सा रंग लेगा?

—'बंबई ब्यूरो' के साथ वशिष्ठ

एमएच दुलारा

अपने टेनिस कोच की नजर में पामेला

"सच पूछिए तो मैं अब तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि जिस पामेला के सेक्स संबंधों को लेकर समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में सुर्खियां लगायी जा रही हैं तथा लेख छापे जा रहे हैं, वह वही पामेला चौधरी है, जो १९८० में लगभग एक साल तक मेरी शिष्या थी। वैसे तो मैं उसे उस समय से जानता था जब वह जयपुर के महारानी गायत्री देवी स्कूल में पढ़ती थी। उस दौरान मैं जयपुर में था। सेंट जेवियर स्कूल और महारानी गायत्री देवी स्कूल में मैं टेनिस सिखाने जाता था। १९८० में मेरा दिल्ली स्थानांतरण हुआ। एक दिन जब मैं प्रशिक्षण के बाद विश्राम कर रहा था, तो अचानक पामेला आयी और मुझसे पूछ बैठी, "श्रीमानजी, क्या आपने मुझे पहचाना?" मैंने 'हां' में उत्तर दिया। उस दिन से वह टेनिस प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम आने लगी। उसकी गतिविधियां देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह टेनिस नहीं सीखना चाहती थी।

उस दौरान मैंने यह भी गौर किया कि पामेला को अच्छे और भड़कीले कपड़ों का बेहद शौक था। जब तक वह स्टेडियम आती रही मैंने उसे दो बार से ज्यादा एक कपड़ा पहने हुए नहीं देखा। सच तो यह है कि लोग जो आज पहनते हैं, उसे पामेला उस वक्त पहनती थी। यही नहीं, लगभग हर पखवाड़े वह अपनी 'हेयर स्टाइल' (केश सज्जा) बदलवा देती थी।

उसी दौरान उसकी कुछ सहेलियों से मुझे पता चला था कि पामेला लड़कों के साथ घूमना-फिरना ज्यादा पसंद करती है। उसकी सहेलियों का कहना था कि पामेला जल्दी से नये दोस्त बनाती है और कुछ दिन के बाद उन्हे छोड़ देती है। एक बार मुझे यह भी खबर मिली कि पामेला अस्पी अस्थाना और अरुण खन्ना नाम के उद्योगपति घराने के लड़कों के साथ ज्यादा समय गुजार रही थी। मुझे याद है कि मैंने उसे एक बार लड़कों के साथ घूमने-फिरने पर डांटा भी था, क्योंकि पामेला की मां जो मुझे जयपुर से ही जानती थीं। मुझसे अकसर पामेला की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करती थीं। एक दिन जब मुझे यह खबर मिली कि पामेला ने शराब पीकर स्टेडियम आना शुरू कर दिया, तो मैंने उसे बहुत डांटा। हालांकि मुझे इस बात की खबर थी कि पामेला सिगरेट बहुत पीती है, किंतु वह शराब भी पसंद करती है, यह मुझे खबर नहीं थी।

मुझे अच्छी तरह याद है कि पामेला उस दौरान अपने से ज्यादा अपने दोस्तों की बात करती थी। हालांकि पामेला देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, किंतु डीलडौल से काफी 'सेक्सी' नजर आती थी। वह शरीर पर चुस्त कपड़े पहनने की आदी थी। मैंने उसे कभी साड़ी या सलवार-कमीज पहने नहीं देखा। वह एक ऐसा लड़की थी जो विवाह की सामाजिक रस्म में विश्वास नहीं करती थी। जब कभी भी शादी-विवाह पर स्टेडियम में बातचीत होती, पामेला विवाह की आलोचना करती। उस दौरान मैंने इस बात पर गौर किया पामेला काममुक्त समाज (सेक्सफ्री सोसायटी) की पक्षधर थी।

कभी-कभी जब पामेला को अपने पिता की याद आती थी तभी वह कुछ क्षणों के लिए भावुक होती थी। वह अकसर अपने पिता को याद करके उनकी बहादुरी के गुणगान करती और बताती कि किस तरह से १९६२ में नेफा मोर्चे पर भारत-चीन युद्ध के दौरान वे शहीद हुए थे।

प्रस्तुति: विवेक शुक्ला

आवासन मंडल

धांधली और अव्यवस्था के घेरे में

वे कहते हैं कि उनकी घोषणाएं पूरी होंगी और मकान के लिए पंजीकृत लोगों के शिकवे दूर होंगे, सपने साकार होंगे। लेकिन उनका रवैया क्या रहा है? किस बुनियाद पर यह माना जाये कि वे ठीक कह रहे हैं?

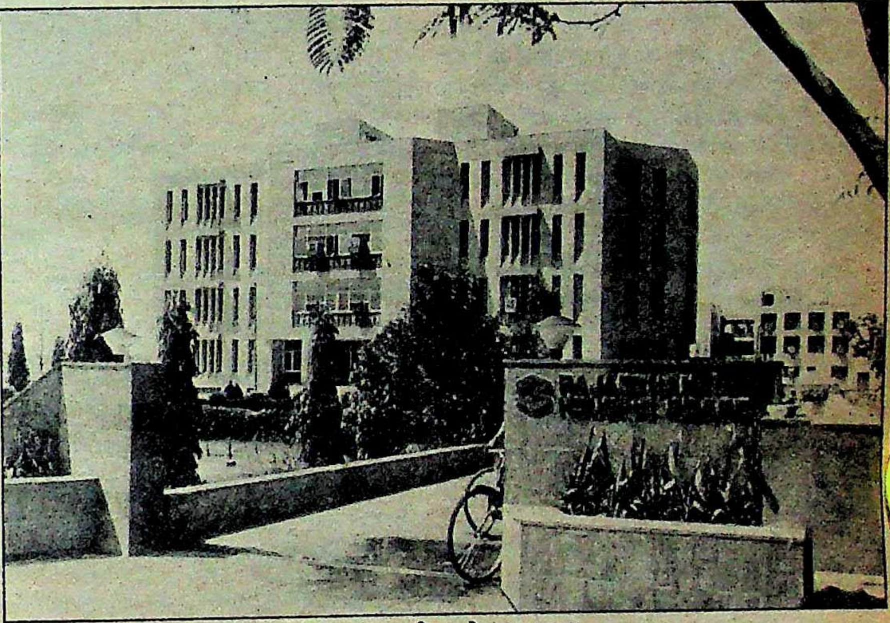

वैभव का विकास: राजस्थान आवासन मंडल की आलीशान इमारत

राजस्थान आवासन मंडल—यह नाम है राजस्थान की एक ऐसी अर्द्धसरकारी संस्था का, जो लोगों को 'अपने घर-आंगन' के सुनहरे सपने दिखाती है। इन सुनहरे सपनों के आकर्षण में लोग राजस्थान आवासन मंडल में पंजीयन करा बैठते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें सपने टूट जाते दिखायी देते हैं। उन्हें बार-बार सांत्वना दी जाती है कि अगले साल मकान मिल जायेगा, दीपावली पर मिल जायेगा या होली पर मिल जायेगा। साल-दर-साल इंतजार और आवासन मंडल के दफ्तर के पचासों चक्कर काटने के बाद जब उन्हें मकान मिलता है, तो वे सिर धुन कर रह जाते हैं कि क्या यही है उनके सपने का घर?

राजस्थान आवासन मंडल के मकानों के निर्माण में किस किस्म की निर्माण सामग्री काम में लायी जाती है, इसका जायजा मंडल के कुछ नवनिर्मित मकानों को देख कर लिया जा सकता है। जगह-जगह उखड़ता प्लास्टर, छत में डली ऊबड़-खाबड़ पट्टियां, हर दीवार पर कम-से-कम एक दरार—यह आवासन मंडल के मकानों की एक आम शक्ल है। एक-दो बरसात की मार से ही मकान ढहने की घटनाएं भी हो चुकी है।

इतिहास: २४ फरवरी, १९७० को अपनी स्थापना के बाद राजस्थान आवासन मंडल ने पहली बार पंजीयन १९७३ में किये थे। हालत यह है कि सैकड़ों आवेदकों को आज सोलह साल बाद भी मकान नहीं मिले हैं। बहुत से आवेदकों ने आवासन मंडल के दफ्तर तक जूतियां घिसते-घिसते अपनी जिंदगी के कई सुनहरे साल गुजार दिये। कई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गये और कुछ मकान का इंतजार करते-करते इस दुनिया को ही छोड़ कर चले गये।

इतने वर्ष गुजर जाने का असर आवेदक के आय-वर्ग पर भी पड़ता है। जिन लोगों ने निम्न आय वर्ग में पंजीयन कराया होता है, उनकी आय बढ़ जाने से वे बड़ा मकान लेना चाहते हैं, मगर ले नहीं पाते। इसी तरह सेवानिवृत्ति या कार्य-क्षमता कम हो जाने से कई बार आय कम भी हो जाती है, मगर उन्हें न चाहते हुए भी ऐसे मकान लेने पड़ते हैं, जिनकी किस्तें चुकाना उनके बूते से बाहर की बात होती है।

इसके बाद भी आवासन मंडल की शरण में जाना लोगों की मजबूरी है। ऐसा करने से एक तो उन्हें एक-मुश्त बड़ी राशि का इंतजाम नहीं करना पड़ता, दूसरे आवासन मंडल की कालोनियां नियमित होती हैं। दूसरी जगह मकान बनाने पर कई तरह की कानूनी पेचीदगियां आती हैं, फिर बिजली-पानी के कनेक्शन की भागदौड़ अलग।

राजस्थान आवासन मंडल में पिछले १५ वर्षों में करीब डेढ़ लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। यानी औसतन १० हजार हर साल मकान के लिए आवेदन करते रहे हैं। लेकिन आवासन मंडल १९८८ के अंत तक इनमें से सिर्फ ८५ हजार लोगों को मकान आवंटित कर पाया है। औसतन, करीब ५६०० लोगों को हर वर्ष मकान दिये जाते हैं। इस समय ६५ हजार से ज्यादा लोग अपने मकान की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इनमें से अधिकतर, आवासन मंडल के अब तक के रवैये को देखकर, यह मान बैठे हैं कि उन्हें अगले ८-१० साल बाद ही मकान मिलेगा। यह मकान के अलावा उनके पास चारा ही क्या है खुद को ढाड़स बंधाने का?

लोग यह भी भली-भांति जानते हैं कि उन्हें मकान कैसा मिलेगा? वे उसी हिसाब से पैसा जोड़ने लगते हैं, ताकि मकान मिलते ही वे उसकी मरम्मत करवा सकें। जयपुर के जवाहर नगर में तो आवासन मंडल के मूल मकानों का नक्शा ही बदल चुका है। एक हाथ से दूसरे और दूसरे से तीसरे में बिकते हुए ये आवासन मंडल के साधारण मकान अब आलीशान कोठियों की शक्ल लेने लगे हैं।

वैसे राजस्थान आवासन मंडल के हाल ही में नियुक्त हुए अध्यक्ष श्रीराम गोटेवाला, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, ने घोषणा की है कि प्रति वर्ष अब तक जहां १५ हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा जाता था, वहीं इस वर्ष ४० हजार नये मकान बनाये जायेंगे। राजस्थान आवासन मंडल की वर्तमान कार्य क्षमता और वहां के अफसरों व कर्मचारियों में नजर आनेवाली आराम-तलबी को देखते हुए गोटेवाला का यह लक्ष्य फिलहाल तो दूर का ढोल ही लगता है। अब अगर वे कोई जादू की छड़ी घुमा दें, तो बात दूसरी है।

राजधानी की हालत: राज्य की राजधानी जयपुर आवासीय समस्या से बुरी तरह ग्रस्त है।

परकोटे के भीतर लोग कीड़े-मकोडे की तरह जिंदगी काट रहे हैं। ऐसे में शहर के आसपास आबादी के लिए आवास की व्यवस्था करना लाजिमी है। लेकिन बदकिस्मती है इस नगर की, कि राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण आदि संस्थायें अपनी सुस्ती और ढुलमुल रवैये के कारण जितने मकान बनाती या भूखंड तैयार करती हैं, उससे बहुत ज्यादा संख्या में अवैध मकान बनकर तैयार हो जाते हैं। ऐसी बस्तियों में न तो सड़कें होती हैं, न जलनिकासी का इंतजाम और न पार्क आदि किसी तरह की जन-सुविधा।

जिस शहर ने अपनी स्थापत्य और नगर-निर्माण कला की धाक समूचे विश्व में जमा रखी है, वहां आज सड़कों पर दिन में पांव रखने की जगह नहीं रहती। यातायात की हालत यह है कि अगर पर्यटक भी नगर की स्थापत्य कला का नजारा लेने के लिए कहीं खड़े होकर सिर उठाना चाहें, तो भारी यातायात के कारण ऐसा नहीं कर सकते।

जयपुर की आवासीय समस्या का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राजस्थान भर में इस समय जो ९५ हजार आवेदक मकान आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें से आधे जयपुर के हैं। जयपुर की आवासीय समस्या को देखते हुए राजस्थान आवासन मंडल के प्रथम अध्यक्ष द्वारकादास पुरोहित ने जवाहर नगर योजना बनायी। फिर मालवीय नगर योजना बनायी गयी। दोनों में दो-दो साल में मकान आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया। मगर हालात ये हैं कि इन योजनाओं में अब तक मकान आवंटित किये जा रहे हैं।

लोगों को अचंभा होता है कि अब तक वर्षों पुरानी कालोनियों में मकान कैसे दिये जा रहे हैं? जानकार लोगों का कहना है कि दोनों ही कालोनियों में काफी संख्या में मकान खाली छोड़े गये हैं। मंडल की पीएसी (संपदा आवंटन समिति) और अध्यक्ष को इन मकानों का आवंटन वरीयता तोड़ कर करने का अधिकार भी है। आरोप लगाया जाता है कि इसी अधिकार के कारण आवासन मंडल के शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। यह सही है कि पर्याप्त संख्या में ऐसे आवंटन ऊंची सिफारिशों के आधार पर 'महत्वपूर्ण, लोगों' को किये जाते हैं, लेकिन दलालों के माध्यम से बड़ी-बड़ी रकमें लेकर इन कालोनियों में मकान देने के भी आरोप कम नहीं हैं।

अपने-पराये की नीति: राजस्थान आवासन मंडल के कई अफसर और कर्मचारी तो सीधे ही अपने रिश्तेदारों या जान-पहचानवालों के जरिये 'प्रापर्टी डीलिंग' के लाभदायक धंधे में लगे हुए हैं। आवासन मंडल की सभी कालोनियों में तीन-चार बोर्ड ऐसे प्रापर्टी डीलरों के नजर आ जायेगें, जो आवासन मंडल के मकान दिलाने का धंधा करते हैं। आवासन मंडल के सूत्रों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर के मंडल के अफसरों या कर्मचारियों से सीधे संबंध हैं। बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि एक-दो अफसर और इंजीनियर खुद ही ये धंधा करते हैं।

साक्षात्कार/ **श्रीराम गोटेवाला**

पहले गड़बड़ियां हुई हैं

राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष श्रीराम गोटेवाला अपनी बेबाकी के लिए प्रदेश में बहुत विख्यात हैं। पहली बार ये जयपुर निर्वाचित होकर विधानसभा में तब पहुंचे, जब श्रीमती गांधी ने जनता सरकार से शासन छीना था। इंका विधायक के रूप में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माथुर को खासा प्रभावित किया और स्वायत्त शासन राज्यमंत्री बन गये। इनकी बेबाकी का यह आलम रहा कि अगली बार चुनावों में इन्हें बिगड़ी छवि बताकर इंका के टिकट से वंचित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जोशी सरकार बनने पर असंतुष्ट के रूप में ये माथुर वफादारी के लिए विख्यात हो गये। नतीजतन शिव चरण माथुर जैसे ही पुनः मुख्यमंत्री बने उन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा देकर राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। बातें आज भी श्रीराम गोटेवाला उसी अंदाज में करते हैं, जिसके कारण इन्हें 'घोटालेवाला' कहा जाने लगा था, पर यह सच है कि जयपुर को लेकर उनके दिल में खासा दर्द है। प्रस्तुत हैं, आवासन मंडल की वर्तमान स्थितियों को लेकर उनसे हुई वार्ता के कुछ अंश—

माया: ***राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं?***

गोटेवाला: राजस्थान के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लाखों लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था करना आवासन मंडल का मुख्य उद्देश्य रहा है।

माया: ***क्या आप सोचते हैं कि मंडल अपने उद्देश्य में सफल रहा है?***

गोटेवाला: निश्चित ही रहा है। इसकी स्थापना से लेकर अब तक ८५ हजार मकान बनाकर आवंटित किये जा चुके हैं।

माया: ***हर वर्ष राजस्थान आवासन मंडल १५ हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखता है। इस बार आपने यह लक्ष्य बढ़ाकर ४० हजार कर दिया है। क्या इतने मकान बनाने का आधारभूत ढांचा मंडल के पास है?***

गोटेवाला: आधारभूत ढांचा हमारे पास मौजूद है। उसे सक्रिय करने की कोशिश कर रहा हूं। अलग-अलग शहरों में इसके लिए व्यवस्था की जा रही हैं।

माया: ***अगर आधारभूत ढांचा पहले से था, तो अब तक ज्यादा मकान क्यों नहीं बन पाये?***

गोटेवाला: जमीन उपलब्ध नहीं थी। अब कई जगह बातचीत कर हम जमीनें ले रहे हैं। अजमेर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, भीलवाड़ा आदि जगह हमने जमीनें ले ली हैं या ले रहे हैं। इस प्रकार राज्य के जिन ३७ स्थानों पर हमारा कार्य चल रहा है, वहां ३१ मार्च, १९९० तक अब तक का कोई भी पंजीकृत मामला विचाराधीन नहीं बचेगा।

माया: ***जयपुर के लिए, जहां राज्य के सबसे ज्यादा आवेदक हैं, कोई विशेष योजना है?***

गोटेवाला: एक तो मानसरोवर योजना है, बयालीस हजार मकानों की। यहां काफी मकान बन भी चुके हैं। सांगानेर योजना के लिए मैंने व्यक्तिगत प्रयास कर भूमि उपलब्ध करायी है। ३१ मार्च, १९९० तक जयपुर तो क्या, पूरे राज्य में कमजोर वर्ग को मकान दे दिये जायेंगे।

माया: ***जयपुर स्थित जवाहरनगर और मालवीयनगर में काफी मकान खाली क्यों छोड़े गये हैं?***

गोटेवाला: जवाहरनगर में कोई मकान खाली नहीं है। दो-तीन फ्लैट मुश्किल से खाली होंगे। बीच-बीच में फ्लैट खाली छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमने तो पैसे लेकर मकान आवंटित कर दिये। यह सही है कि कुछ लोगों ने 'इन्वेस्टमेंट' के तौर पर पैसा लगा रखा है। वे वहां रह नहीं रहे। इस सिलसिले में हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मालवीयनगर में कुछ फ्लैट खाली हैं, जिनका आवंटन हम अभी कर रहे हैं।

माया: ***आवासन मंडल के निर्माण व गुणवत्ता के बारे में आमतौर पर अच्छी राय नहीं है।***

इसको सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं आप?

गोटेवाला: हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन है। उसको काफी मजबूत बनाया गया है। नये अधिशासी अभियंता लगाये गये हैं। वैसे, ऐसी बात नहीं है कि हमारे मकान इतने खराब हों। आप खुद का मकान भी बनायेंगे, तो थोड़ी बहुत दरार बगैरह तो आ ही जाती है। मानते हैं, कुछ कमियां हैं। उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

माया: ***विशिष्ट पंजीकरण योजना में जिन सांसदों व विधायकों ने आवेदन किया था, उनमें से ज्यादातर को मकान मिल चुके हैं। मगर मालूम पड़ा है उनमें से कोई भी उन मकानों में नहीं रह रहा है।***

गोटेवाला: कुछ तो रह रहे हैं। राम नारायण चौधरी रह रहे हैं। महादेव सिंह जी के घर भी मैं गया था। खुला मकान था। पता नहीं, कौन रह रहा है?

माया: ***पर वे तो सैकड़ों की संख्या में हैं।***

गोटेवाला: हैं साहब। पर इतना ही कह सकता हूं कि उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे रहना चालू करें।

माया: ***ऐसा कहा जाता है, कुछ प्रापर्टी डीलर आवासन मंडल के मकान दिलाने का दावा करते हैं। मंडल के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी यही काम करते हैं, ऐसा आरोप है। उन पर नजर रखने के लिए क्या किया जाता है?***

गोटेवाला: मकान या तो लाटरी से दिये जाते हैं या पीएसी (प्रापर्टी अलाटमेंट कमेटी) प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न वर्गों को मकान देती है। पहले गड़बड़ियां हुई भी हैं, मैं इनकार नहीं करता। पर अब तो मैंने बहुत सख्ती कर दी है।

माया: ***पंजीयन कराते समय जिस कालोनी में तथा जिस आकार व दर पर मकान देने की बात कही जाती है, वैसा किया नहीं जाता। दर बढ़ जाती है, आकार कम हो जाता है तथा कालोनी भी बदल जाती है। ऐसा क्यों?***

गोटेवाला: केवल १९७३ के पंजीयन के समय ऐसा वायदा किया गया था। उसके बाद इस तरह का वायदा हम नही करते, क्योंकि जमीन की दर हर साल बढ़ जाती है। 'सेल्फ फाइनेंसिग स्कीम' में जरूर हम उसी दर व आकार में तथा दो साल की अवधि में मकान दे देते हैं।

माया: ***अनुसूचित जाति व जनजाति के बाद मकानों में सबसे बड़ा आरक्षित कोटा मंडल ने अपने कर्मचारियों का रखा है। इससे आम लोगों को मकान देर से मिलता है। क्या ऐसा करना ठीक है?***

गोटेवाला: अब मंडल के कर्मचारियों का ज़्यादा कोई कोटा बकाया रहा ही नहीं है। हरेक को रहने का अधिकार तो है ही। मैं तो ऐसी व्यवस्था करना चाहंता हूं कि आज आप मेरे पास आयें, तो मैं तुरंत दिखा सकूं कि ये मकान बने हुये हैं। आपको लेना है, तो ले लीजिये। पर इस व्यवस्था के लिए थोड़ा समय लगेगा। हम सारी मशीनरी को 'गियर अप' कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की स्थिति आ पाये, लेकिन अभी तो ये स्वप्न ही है।

माया: ***कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि १९७३ के पंजीकृत आवेदकों के लिए मकान बनाने के लिए 'हुडको' से जो ऋण लिया गया, वह पैसा मालवीय नगर में मंडल कर्मचारियों के लिए जो मकान बनाये जा रहे हैं, उसमें लगा दिया गया?***

गोटेवाला: पुराने समय में लगाया होगा, अभी तो हम नहीं लगा रहे। लेकिन 'हुडको' से हम जिस काम के लिए ऋण लेते हैं, उसी काम में लगता है। 'हुडको' वाले भी जांच करते हैं।

माया: ***वैसे मकान तो बनाये जा रहे हैं, मालवीय नगर में?***

गोटेवाला: हां, मकान बनाये जा रहे हैं।

माया: ***जनता के प्रति यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं होने की काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। इस दिशा में कुछ कर रहे हैं आप?***

गोटेवाला: चेयरमैन के प्रति तो शिकायतें नहीं मिलतीं न! मैं स्वयं यहां १० से ५ बजे तक रहता हूं। कोई भी सीधे मिल सकता है। मैं स्वयं मानता हूं कि अधिकारियों और कर्मचारियों का जनता के प्रति व्यवहार संवेदनशील रहना चाहिए। फिर भी, जो कोई भी मेरे पास शिकायत लेकर आता है, उसे देखता हूं और शिकायत को रफा-दफा करने की कोशिश करता हूं।

माया: ***आपने अध्यक्ष बनते ही कलाकार नगर, नीति नगर आदि बनाने की घोषणाएं कीं। आप मानते हैं, ये पूरी हो सकेंगी?***

गोटेवाला: निश्चित रूप से पूरी होंगी। मैंने सोच-समझ कर ये घोषणाएं की हैं। मालवीयनगर में नीतिनगर के लिए सड़क आदि का काम शुरू हो गया है। कलाकारनगर के लिए भी मैंने कला संस्थाओं को जमीनें बता दीं। अब ये उनके जिम्मे है कि कब वे पंजीकरण कराती हैं। उनकी तरफ से ही मांग आ रही है कि तारीखें बढ़ा दो। इसी तरह विश्वविद्यालय के शिक्षकों, डाक्टरों, साहित्यकारों आदि के लिए भी हमने जमीनें रखी हैं। अब ये बात दूसरी है कि जो जमीनें रखी हैं, उन पर कोई 'स्टे' आ जाये। उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आमतौर पर जो विवादहीन जमीनें हैं, उन्हीं पर इस तरह की योजनायें बना रहे हैं।

—भुवनेश जैन

ये लोग अपने किसी ऐसे रिश्तेदार या जानकार के नाम से पंजीयन करा देते हैं, जिसे मकान की जरूरत ही नहीं होती। पंजीयन होने के बाद ये ग्राहक तलाशते हैं। ग्राहक मिल जाने पर जोड़-तोड़ बिठा कर मकान आवंटित करा लिया जाता है। मजे की बात यह है कि और लोगों को मकान मिलने में चाहे कितनी ही दिक्कतें क्यों न हों, आवासन मंडल के कर्मचारियों के लिए ऐसा बिलकुल नहीं है। अपने कर्मचारियों के लिए मंडल ने एक निश्चित कोटा आरक्षित कर रखा है। यह कोटा अनुसूचित जाति और जनजाति के बाद सबसे बड़ा कोटा है। कर्मचारियों के बाद सांसदों, विधायकों, पत्रकारों, पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और विकलांगों का नंबर आता है। आम लोगों को जयपुर में जवाहर नगर या मालवीय नगर के खाली फ्लैट नहीं दिये जाते, वहीं मंडल कर्मचारियों को ये आसानी से दिये जा रहे हैं। उन्हें पहले से मालूम रहता है कि किस कालोनी में कौन-सा फ्लैट खाली है।

इन दिनों जयपुर की मालवीय नगर कालोनी में मंडल कर्मचारियों के लिए ३०० नये मकान प्राथमिकता के आधार पर तैयार किये जा रहे हैं, जबकि आम लोगों को जवाहर नगर और मालवीय नगर जैसी शहर के नजदीक स्थित कालोनियों में मकान आवंटित करना कब से ही बंद किया जा चुका है। उन्हें सांगानेर कस्बे से कुछ पहले बन रही मानसरोवर कालोनी में मकान दिये जा रहे है। वर्ष १९७३ के आवेदकों के संगठन 'आवासीय समस्या समिति' के अध्यक्ष बीके भारतीय आरोप लगाते हैं कि 'हुडको' ने १९७३ के आवेदकों के लिए मकान बनाने के लिए जो पैसा दिया, उसे मंडल अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने में लगा रहा है।

इस आवासीय समस्या समिति की भी दिलचस्प कहानी है। जब १३ वर्ष तक, १९७३ में पंजीकृत आवेदकों में आवंटन से बचे हजारों आवेदकों की सुध नहीं ली गयी, तो एक स्कूल अध्यापक बीके भारतीय ने, जो आज कांग्रेस (इ) से जुड़ गये हैं, उन आवेदकों को संगठित करने का निर्णय लिया। अखबारों में खबर देकर उन्होंने आवेदकों को एक दिन जयपुर के रामनिवास बाग में इकट्ठा किया और अपना मकान प्राप्त करने के लिए मिल-जुल कर आवाज उठाने का आह्वान किया। भारतीय के अनुसार उनके इस कदम से आवासन मंडल के कुछ अधिकारी भड़क उठे। उन्होंने (अधिकारियों) कहा, "यह नेतागिरी करता है। इस तरह मकान कभी नहीं दिये जायेंगे।" लेकिन भारतीय तथा उनके साथी, समिति के महामंत्री हजारीलाल आदि ने अपनी लड़ाई जारी रखी। नतीजा सामने आया। आवासन मंडल के अधिकारियों को झुकना पड़ा। तब जाकर यह स्थिति आयी है कि अब १९७३ के करीब ६०० आवेदक ही आवंटन से बचे हैं, वरना चार साल पहले यह संख्या हजारों में थी। १९७३ के आवेदकों से वादा किया गया था कि उन्हें जवाहर नगर में मकान दिया जायेगा। लेकिन इन्हें अब मालवीय

नगर या मानसरोवर कालोनी में मकान दिये जा रहे हैं। आवेदन करते समय जो दर तय हुई थी, आज उसकी कई गुना रकम उन्हें देनी होगी। मकान का आकार भी पहले के मुकाबले काफी कम रह गया है।

राजस्थान आवासन मंडल इस समय राज्य के ३६ बड़े-छोटे शहरों में मकान बना रहा है। इनमें पंजीयन कर लेने के बाद भी मकान न पाने का एक बड़ा कारण होता है, जमीन का न मिल पाना। अगर जमीन मिल जाती है, तो वह कानूनी विवाद में उलझ जाती है और मकान नहीं बन पाते। वर्ष १९८७ तक आवासन मंडल के लिए राज्य भर में कुल साढ़े सात हजार एकड़ भूमि हासिल की गयी। भरतपुर, झालावाड़ा, सिरोही जैसे शहरों में १० एकड़ से भी कम भूमि मंडल हासिल कर पाया। गोटेवाला ने जरूर अब इस दिशा में गति लाने का प्रयास किया है। इस वर्ष वे जोधपुर, उदयपुर, अलवर, सिरोही, भीलवाडा व अजमेर में काफी जमीन मंडल के लिए लेने में सफल हो गये हैं। देखना यह है कि इन पर मकान कब तक बनने लगेंगे और कब लोगों को दिये जायेंगे। गोटेवाला का दावा है कि ३१ मार्च १९९० तक राज्य के सभी शहरों में इस समय तक प्रतीक्षारत सभी आवेदकों को मकान दे दिये जायेंगे।

सिर्फ दावा: विभिन्न शहरों में मंडल के मकानों के लिए प्रतीक्षारत आवेदकों की सूची देखें, तो लगता है कि उनका दावा भी एक स्वप्न है जो वे जनता को दिखा रहे हैं। आवासन मंडल ने अगर अपने लक्ष्य के बराबर ४० हजार मकान बना भी लिए, तो भी समस्या हल नहीं हो पायेंगे, क्योंकि प्रतीक्षारत आवेदकों की संख्या करीब ६५ हजार है। अकेले जयपुर में ३० हजार से ज्यादा आवेदक मकानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि जयपुर में इस वर्ष १५ हजार नये मकान ही बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना लक्ष्य अब से पहले पूरे राज्य के लिए रखा जाता था, और वह भी मुश्किल से ही पूरा हो पाता था।

जनता के सपने पूर हों, न हों, आवासन मंडल के बहुत से अधिकारी और कर्मचारी शानदार जीवन बिता रहे हैं। 'प्रापर्टी डीलिंग' के जरिये कुछ अदना कर्मचारी भी आज शान से कारें चलाते दिखायी देते हैं। आवासन मंडल की आलीशान बहुमंजिली इमारत में अध्यक्ष तथा आयुक्त के वातानुकूलित कमरे हैं जिनका वैभव किसी महल के कक्ष से कम नहीं है।

इस बीच आवासन मंडल बीसियों नयी योजनाएं शुरू कर चुका है। ''पारिजात'', 'कुबेर', 'कल्पतरु' आदि इन नयी योजनाओं में मंडल दो से छह वर्ष तक में मकान देने की गारंटी देता है। लेकिन क्या मंडल इन योजनाओं में अपने इतिहास को नहीं दुहरायेगा? वह भी तब, जबकि इसकी कार्यशैली तथा इसके कर्मचारी, सब पूर्ववत् बने हुए हैं।

जनता के सपने पूरे हों, न हों, आवासन मंडल के बहुत से अधिकारी और कर्मचारी शानदार जीवन बिता रहे हैं। 'प्रापर्टी डीलिंग' के जरिये कुछ अदना कर्मचारी भी आज शान से कारें चलाते दिखायी देते हैं। आवासन मंडल का दफ्तर भी ऐसा शानदार है कि लगता नहीं है कि यहां धन की कहीं कोई कमी है। मंडल की आलीशान बहुमंजिली इमारत में अध्यक्ष तथा आयुक्त के वातानुकूलित कमरे हैं, जिनका वैभव किसी महल के कक्ष से कम नहीं है। मंडल के रोजमर्रा के कार्य आधुनिक इलेक्ट्रानिक मशीनों पर होते हैं।

कुछ भी हो आम जनता आवासन मंडल से बुरी तरह त्रस्त है। अपनी समस्या लेकर वहां जाने पर अधिकारी व कर्मचारी उन्हें जिस तरह दुत्कराते हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि यह दफ्तर जन कल्याण का दावा करने वाली किसी सरकार से जुड़ा है।

—भुवनेश जैन

अप्रैल, '८९

मनोहर कहानियां

प्रेम-अपराध कथा विशेषांक

दो लड़कियों की प्रेम कहानी बनाम यौन-परिवर्तन

दिल्ली की दो लड़कियों, मंजु और मधु के बीच प्रेम इतना गहराया कि उन्होंने कभी जुदा न होने का फैसला कर लिया।

अंधेरे में उजाला

पटना के एक नेत्रहीन, किन्तु प्रतिभाशाली अंग्रेजी प्रवक्ता और एक सुशिक्षित युवती के प्रेम-विवाह की प्रेरक कथा।

जीत : प्रेम कथा जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची

दिल्ली के एक युवक और एक युवती ने अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए शादी तो कर ली, लेकिन उनके दाम्पत्य-जीवन में ऐसे टकराव, तनाव और कानूनी मुद्दे आये कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।

नीतू और पटना के एक इंजीनियर का पत्र

पहले पति से त्रस्त नीतू अपनी मां और मौसी के पास पटना क्या आयी कि एक कथित सेक्स-स्कैण्डल में फंस गयी, फिर एक इंजीनियर ने उसे नौकरी और घर के साथ संरक्षण दिया, तो नया स्कैण्डल उठ खड़ा हुआ।

अन्य अनेक मर्मस्पर्शी एवं सत्य प्रेम-कथाएं

मप्र खनिज निगम

प्रबंध-संचालक क्यों हटाये गये ?

मप्र खनिज निगम के प्रबंध निदेशक के पद से एमसी मजूमदार को बेआबरू होकर हटना पड़ा। उनकी इस तरह विदाई आमतौर पर निगम के अध्यक्षों की विजय मानी जाती रही है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है, जो मजूमदार की कारगुजारियों से जुड़ी है। क्या है वह वास्तविकता और मजूमदार की कारगुजारियां क्या हैं ?

मप्र में अनेक सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों एवं प्रबंध संचालकों के मध्य रार और तकरार की घटनाएं अब दिनोदिन उजागर होती जा रही हैं। विगत अंतराल में इस प्रकार की घटनाओं में तेजी आयी है। मप्र राज्य परिवहन निगम में अध्यक्ष व प्रबंध संचालक के मध्य तनातनी को अधिक समय नहीं गुजरा है। दोनों महानुभावों में इस कदर ठनी कि दोनों को पद से हाथ धोना पड़ा। रापनि का प्रसंग इस मायने में भिन्न था कि वहां टकराव दो आईएएस अधिकारियों के बीच था। इसके विपरीत मप्र लघु उद्योग निगम और मप्र खनिज निगम के प्रबंध संचालकों-मंजोत्रा और एससी मजूमदार को अपने-अपने निगम के अशासकीय अध्यक्षों से टकराने का परिणाम भुगतना पड़ा। इनके बेआबरू होकर कूचे से निकलने को हालांकि अध्यक्षो की विजय माना जा रहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि इन्होंने अपनी विदायी का सामान खुद-ब-खुद जुटाया। हठ और हेठी इन दोनों प्रबंध संचालकों को ले डूबी। इनकी रीतिनीति और इनका आचरण उपरोक्त निगमों से इनके पलायन का बायस बना। मप्र खनिज निगम को लें। निगम के एमडी सुभाषचंद्र मजूमदार ने नये चेयरमैन विलास लाड से पंगा तो लिया ही, दूसरे उनकी कारगुजारियां भी ऐसी थीं कि यदि वे ज्यादा दिन टिके रहते, तो शायद निगम को ले डूबते।

मुख्यमंत्री वोरा के स्पष्ट आदेशों के बाद भी एमडी ने निलंबन आदेश जारी करने में ढिलाई बरती।

दोहन : खनिज निगम की स्थापना १९ जनवरी, १९६२ को प्रदेश में उपलब्ध खनिज ससाधनों के सुचारु और सुविचारित दोहन और उन पर आधारित कारखानों की स्थापना के प्रयोजन से हुई थी। वीसी वर्मा व वीसी पाठक सदृश प्रबंध संचालकों ने इसे सुदृढ़ आधार और निश्चित दिशा प्रदान की। कई वर्षों तक निगम ठीकठाक चलता रहा, लेकिन इसे ग्रहण तब लगा, जब १ अगस्त, १९८७ को रायगढ़ के चर्चित पूर्व जिलाधीश एससी मजूमदार को निगम का एमडी बनाया गया। वे रायगढ़ में बतौर कलेक्टर विवादास्पद रहे थे और सामान्य प्रशासन विभाग में भोपाल में दिन काट रहे थे। बताते हैं कि उन्हें विभागीय जांच का भी सामना करना पड़ा था। दिन फिरे, तो मजूमदार निगम के एमडी तो बने, किंतु उनकी वोरा के गृहनगर दुर्ग के रामानुजलाल यादव (चेयरमैन) से निभी नहीं। दुर्ग में वोरा की 'त्रयी' के सदस्य यादव की शक्ति और सामर्थ्य रंग लाती, इसके पहले ही फरवरी '८८ में अर्जुन सिंह बतौर मुख्यमंत्री लौट आये। लिहाजा मजूमदार की विदायी टल गयी, उल्टे यादव को पद से हाथ धोना पड़ा। इस घटनाक्रम ने एमडी महोदय की सत्ता और शक्ति को सींच-सा दिया। रायपुर में निगम का कोई बड़ा या खास काम नहीं है, लेकिन एमडी ने रायपुर की ताबड़तोड़ यात्राएं कीं। दिखाने को सरकारी कामकाज का पुछल्ला था, मगर एक कारण यह भी था कि रायपुर में अनुपम नगर में टीवी टावर के पास उनका आलीशान मकान बन रहा था। प्रवास के दरम्यान सुविधा हेतु रायपुर में शंकरनगर में एक मकान में गेस्टहाउस बनाया गया, जिसे टीवी, एयरकंडीशनर और आधुनिक फर्नीचर से सुसज्जित किया गया। यह सारा व्यय निगम के खाते में गया। इसी क्रम में जगदलपुर में भी निगम के व्यय पर गेस्टहाउस का निर्माण किया गया। यह सब उस दौर में हुआ, जब प्रदेश सूखे की विभीषिका से जूझ रहा था और मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता के निर्देश दे रखे थे।

मनमर्जी : मजूमदार के कार्यकाल में निगम में रिकार्डतोड़ तबादले हुए। निगम में रेत-खदानों का प्रभारी पद दुधारू माना जाता है। इन पदों पर नियुक्तियों में नियम-कायदों को खूब ठेंगा दिखाया गया। डबरा, देवास, जबलपुर और बिलासपुर आदि जगहों के उदाहरण सामने हैं। मुरैना में चतुर्थ श्रेणी अधिकारी एमडी की कृपा से प्रभारी बन गया। निगम खनिजों की बिक्री के लिए विधिवत निविदाएं आमंत्रित करता है। यहां अधिक रेट के बजाय कम रेट भरनेवाले कुछ लोगों को केवल इसलिए प्रश्रय दिया गया, ताकि कुछ चहेते ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुंचे। बताते हैं कि मजूमदार दुर्ग के एक ट्रांसपोर्टर पर विशेष रूप से कृपालु रहे। हाल में, जगदलपुर में उपमहाप्रबंधक (भौमिक) केएस सिंहल को रिश्वत लेते रंगे-हाथों पकड़ा गया। मुख्यमंत्री वोरा के स्पष्ट आदेशों के बाद भी एमडी ने निलंबन आदेश जारी करने में ढिलाई बरती। जानकार सूत्रों के अनुसार कंपनी सचिव एमपी श्रीवास्तव एवं अन्य दो अधिकारी तमाम कृत्यों में एमडी के सहयोगी रहे हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मप्र में किसी को सरकारी नौकरी में लेना सबसे दुष्कर काम है, परंतु खनिज निगम में बगैर पद विज्ञापित किये और बगैर निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन किये दर्जनों को नियुक्तियां दी गयीं। 'माया' संवाददाता ने श्रम एवं समयसाध्य खोजबीन से जो सूचनाएं अर्जित कीं उनके अनुसार ४ अगस्त '८७ से ६ फरवरी '८९ के मध्य १० युवतियों समेत ६६ व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गयीं। इन नियुक्तियों की आड़ में कहीं कोई गोरखधंधा नहीं हुआ होगा, यह विश्वास करना मुश्किल है।

निरंकुश : निगम के हितों की अवज्ञा का आभास कुछ और बातों से भी मिलता है। मैनपाट (सरगुजा) में विभागीय काम बंद कर ठेकेदारी प्रथा शुरू की गयी और १६० रुपए प्रतिटन की

निविदा को ठेका न देकर २०७ रुपए की निविदा के केएन सिंह एंड कंपनी को करीब दो करोड़ रुपयों का ठेका दिया गया। और-तो-और, प्रबंध-संचालक ने १५ फरवरी '८६ को ३० लाख रुपयों के भुगतान-चेक पर हस्ताक्षर किये, जबकि वह उन दिनों अवकाश पर थे और अनेक भुगतान-चेकों को उन्होंने बगैर दस्तखत किये लौटा दिया था।

एमडी की एक और कारगुजारी देखिए। बाराद्वार में खदान से रेलवे साइडिंग तक ८ किमी पत्थर ढुलाई का ठेका १४ रुपए प्रति टन पर दिया जाता है। यहां मिट्टी ढुलाई का ठेका २० रुपए प्रतिटन पर दिया गया। ये आदेश पांच-पांच हजार टन की किश्तों में दिये गये, क्योंकि एमडी को एक बार में एक लाख रुपए तक आदेश जारी करने का अधिकार है। निगम के हितों पर विशेष ध्यान न देने का ही यह नतीजा है कि बम्हनीबंजर, सतना, केशकाल और मेघनगर की खदानें कई-कई दिन बंद रहीं। राकफास्फेट पर आधारित प्रस्तावित कारखाने की स्थापना के सिलसिले में वे सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की जुगत भिड़ाने में लगे रहे। मप्र खदान स्वतंत्र मजदूर संगठन, बाराद्वार, बिलासपुर के जनरल सेक्रेटरी बेनीराम साहू से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मजूमदार पर कई तीखे आरोप लगाये। उन्होंने बताया कि एमडी के खिलाफ एक ज्ञापन वे मुख्यमंत्री को भी सौंप चुके हैं। साहू के आरोप हैं कि मेघनगर में काफी समय से राकफास्फेट की अवैध ढुलाई की जा रही है, जीसीबी मशीन से खुदाई का हिसाब-किताब नहीं रखा जाता और प्रबंधक के खिलाफ शिकायत-दर-शिकायत पर इस कारण ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सारे घपले-घोटाले में एमडी मजूमदार की मिलीभगत है। शिकायतें जब सीएम तक पहुंचीं और पानी सिर के ऊपर से बहने लगा, तो अंततोगत्वा मार्च के तीसरे हफ्ते में मजूमदार को पद से हटा दिया गया। मजूमदार से उनका पक्ष जानने के लिए 'माया' संवाददाता ने घर और दफ्तर में कई बार संपर्क किया, किंतु वे कन्नी काटते रहे।

फिलहाल, ताजा स्थिति यह है, और एक तरह से कथा का क्षेपक भी, कि खनिज निगम से विदा होकर मजूमदार सरकारी मुद्रणालय के नियंत्रक बन गये हैं। रायगढ़ में कलेक्टर-काल के उनके कृत्यों की जांच पहले भी हो चुकी है। निष्कर्ष हालांकि पता नहीं हैं, मगर सबसे अहम प्रश्न, जो अनुत्तरित है, वह यह है कि इसकी क्या गारंटी है कि बिगड़े ढर्रे के आदी मजूमदार शासकीय मुद्रणालय में गुल नहीं खिलायेंगे? नीति-निर्माताओं को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि अड़ियल और भ्रष्ट नौकरशाहों को कैसे सबक सिखाया जाये, जिससे वे शासकीय व लोकहितों की अवज्ञा-अवहेलना तथा भ्रष्टाचरण से बाज आयें? यह इसलिए भी अहम व आवश्यक है, क्योंकि मप्र में और भी कई नौकरशाह ऐसे हैं जो मजूमदार की भांति 'विलोम गति' के आदी हैं।

—सुधीर सक्सेना, बाराद्वार से

आहत को राहत

उपेक्षा का अंदेशा: अर्जुन सिंह

पिछले दिनों अर्जुन शिविर के लगभग पचास लोग, जिनमें ज्यादातर विधायक थे, दिल्ली गये और उन्होंने अंग्रेजी में अत्यंत सलीके से ड्राफ्ट शिकायतनामा आलाकमान को सौंपा। दिल्ली में इन लोगों की भेंट १५ मार्च को वसंत साठे और १६ मार्च को जनार्दन पुजारी से हुई। साठेजी मप्र के मर्माहत नेताओं से फुरसत से बतियाये और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी चर्चा का हवाला देकर उन्हें ढाड़स बंधाया कि मप्र में अर्जुन सिंह की उपेक्षा नहीं की जायेगी और न ही उनके समर्थकों को प्रताड़ित किया जायेगा। साठे के इन मिठासभरे बैनों यानी मीठे बचनों से मर्माहतों को काफी राहत मिली है। इस गुट की प्रमुख शिकायत है कि वोरा इकतरफा चाल चल रहे हैं। वैसे, वोरा ने अभी तक राजनीतिक शतरंज की बिसात पर ऊंटों और घोड़ों को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन मंडीदीप, विलासपुर, चंदेरी, खजुराहो और हरदा के प्राधिकरणों में पदस्थ प्यादों—मोहम्मद अकबर, अनिल टाह, बहादुर सिंह चंदेल और गुलाब सिंह बघेल को वह ढेर कर चुके हैं। वोरा के तेवरों से शिविर में धुकधुकी मची है। आलाकमान को सौंपे ज्ञापन में एक बात आश्चर्यजनक यह है कि उसमें सुभाष यादव, अजीत जोगी और अजीज कुरेशी की अलग-अलग रिपोर्टों के अलावा सांसद केएन प्रधान की बीड़ी मजदूरों से संबंधित रिपोर्ट को भी लागू करने की मांग की गयी है। यह बात आश्चर्यजनक इसलिए है, क्योंकि प्रधान अर्जुन-विरोधी खेमे में गिने जाते हैं। वैसे पिता-पुत्र (केएन और प्रमोद) की खूबसूरत खूबी यह है कि उन्होंने सिंधिया और कमलनाथ को एक साथ साध रखा है। समझ में नहीं आता कि केएन प्रधान की रिपोर्ट पर अमल की चिंता अर्जुन गुट को क्यों है? वैसे अर्जुन शिविर के जो लोग दिल्ली गये, उनमें मंजुराय उइके, रामेश्वर पटेल, चरणदास महंत और हनुमंत सिंह जैसे पूर्व मंत्री, करुणा दांगी, प्रभा भार्गव [illegible] महिला विधायक और मुकेश नायक, देवेंद्र सिंह और रमाशंकर सिंह जैसे युवा विधायक भी थे। इस टोली में वह ठाकुर हरवंश सिंह भी थे, जिनका चार इमली स्थित बंगला जनवरी के नाटकीय घटनाक्रम में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुका है।

दो पाबंदियां

सलमान रुश्दी की किताब पर पाबंदी और उनकी हत्या के फतवे पर हो-हल्ला जारी है। ऐसे शोरोगुल में मप्र के एक पिछड़े हुए जिले और औद्योगिक तीर्थ में लेखक और कलाकार पर प्रतिबंध की ओर ध्यान देने की फुरसत भला किसे है? मप्र में लेखकीय स्वतंत्रता का दम भरनेवाली संस्थाओं की कमी नहीं है। अनूठे सांस्कृतिक आयोजनों में मप्र देश में लासानी है। परंतु बालाघाट में एनएल खोबरागड़े की पुस्तक 'भारत की विकृत समाज व्यवस्था' को प्रतिबंधित कर उसे जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। यथार्थ प्रकाशन, कोसमी, बालाघाट इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। जिला पुलिस अधीक्षक बीडी सिंह के अखबारी बयान पर यकीन करें, तो भादंसं की धारा १५३ ए के तहत इसके खिलाफ अपराध दर्ज कर इसे जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है और अब तक २५ प्रतियां जब्त की जा चुकी हैं। यह तो हुई एक किताब पर पाबंदी की बात। रही सही कसर भोपाल इस्पात संयंत्र ने पूरी कर दी है। संयंत्र ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति की पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजनवाई को पाबंदियों से जकड़ दिया है। इस पाबंदी के तहत तीजन अब किसी भी अखबार या पत्र समूह को इंटरव्यू या बयान नहीं दे सकेगी। अंगूठाछाप निरक्षर तीजन भिलाई इस्पात संयंत्र में भृत्य के पद पर कार्यरत है। देखना यह है कि संयंत्र अपना तुगलकी आदेश वापस लेता है या फिर महाभारत के कीचकवध जैसे प्रसंगों को अत्यंत सहजता से निभानेवाली तीजन पडवानी की खातिर नौकरी को लात मारती है। किसी कलाकार पर इस तरह का प्रतिबंध अनहोनी घटना है, किंतु जहां तक किताब पर प्रतिबंध की बात है, स्व० गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कृति मप्र में बरसों प्रतिबंधित रह चुकी है।

तीजन अब किसी भी अखबार या पत्र समूह को इंटरव्यू या नहीं दे सकेगी। देखना यह है कि संयंत्र अपना तुगलकी आदेश वापस लेता है या तीजन पंडवानी की खातिर नौकरी को लात मारती है।

—सुधीर सक्सेना

तारिक अनवर

मंत्री की कुरसी क्यों ठुकरायी थी ?

कटिहार के वर्तमान इंका सांसद और बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तारिक अनवर की प्रतीक्षा में सत्येंद्र नारायण सिंह की काबीना की एक कुरसी अभी तक क्यों खाली पड़ी है ? क्या तारिक अंत तक यह कुरसी नहीं कबूलेंगे ? जगन्नाथ मिश्र से उनकी क्या नाराजगी है ? क्या बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति में तारिक बगावत की तुरही बजायेंगे ?

सत्येंद्र नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री की खाली कुरसी का विवाद अभी तक सुलझ नहीं सका है। दरअसल, काबीना मंत्री की इस कुरसी पर न बैठने की जिद कटियार के इंका सांसद और बिहार प्रदेश कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तारिक अनवर ने ठान रखी है। नतीजतन, इस खाली पड़ी कुरसी पर तरह-तरह के अटकलों की धूल जमती जा रही है। तारिक अनवर आखिरकार झख मारकर इस कुरसी पर आकर बैठेंगे या इस कुरसी पर बैठने का दंश किसी भी सूरत में सहन करने को तैयार नहीं होंगे, इसको लेकर पटना के राजनीतिक गलियारों में तर्क-वितर्क जारी है। इस मसले पर अंत में ऊबकर मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह को भी यह कहना पड़ा कि तारिक अनवर मेरी काबीना में शपथ लेंगे या नहीं, इसका फैसला आलाकमान ही करेंगे, क्योंकि उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में बिठाने का निर्देश आलाकमान का ही था। ऐसा कहकर सत्येंद्र नारायण सिंह अपनी जिम्मेदारी से ही सिर्फ मुक्त नहीं हुए, बल्कि परोक्ष रूप से तारिक को आड़े हाथों भी लिया कि आलाकमान की इच्छा की अवमानना करनेवाले के बारे में तो स्वयं आलाकमान ही कोई निर्णय ले सकते हैं। बिहार के एक पूर्व राज्यमंत्री और तारिक अनवर के कटु आलोचक 'माया' से कहते हैं, "तारिक को यह कुरसी कबूलनी ही होगी। लड़ाकू तो कभी वे रहे नहीं हरदम सीताराम केसरी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। बिहार जैसे प्रदेश में कांग्रेस की विक्षुब्ध राजनीति थामने का दम भला उनमें कहां से होगा ? इसलिए तारिक अनवर रातोरात अचानक शेर बनकर दहाड़ने लगेंगे, यह सोचना ही हास्यास्पद है।"

एक ओर तो बिहार की नयी काबीना में मंत्री न बनाये जाने के कारण यादव राजनीति के महंत रामलखन सिंह यादव सहित अनगिनत दिग्गज नाराज हैं, तो दूसरी ओर तारिक अनवर को गुस्सा इस बात का है कि बिहार में मंत्री पद का प्रस्ताव उन्हें क्यों दिया गया ? बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मंत्री बनाये जाने की वजह से कोई नाराज हो गया हो। स्व० केदार पांडेय और स्व० दारोगा राय ने तो बिहार का मुख्यमंत्री पद सुशोभित करने के बाद भी बिहार सरकार में मंत्री पद सहर्ष कबूल किया था। हां, डेढ़ साल पहले ऐसी एक घटना राजस्थान में हुई थी, जब बिहार के वर्तमान राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाडिया ने शिव चरण माथुर की सरकार में बतौर मंत्री शपथ लेने से इनकार कर दिया था। इसलिए ११ मार्च को जब पटना के राजभवन में जगन्नाथ पहाड़िया सत्येंद्र नारायण सिंह सहित उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण करवा रहे थे और तारिक अनवर ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, तो पहाड़िया को भले ही इस पर अधिक आश्चर्य नहीं हुआ हो, पर राजभवन में उस समय मौजूद बिहार के तमाम राजनीतिक धुरंधर भौचक्के रह गये थे। यों सबको यह पता था कि प्रदेश में मंत्री बनाये जाने के आलाकमान के फरमान से तारिक तिलमिलाये हुए हैं, पर किसी को इस हद तक उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की परजीवी परंपरा का यह महत्वाकांक्षी युवा राजनीतिज्ञ विद्रोही भंगिमा अख्तियार कर आलाकमान के हुक्म को टाल देने का दुस्साहस कर देगा।

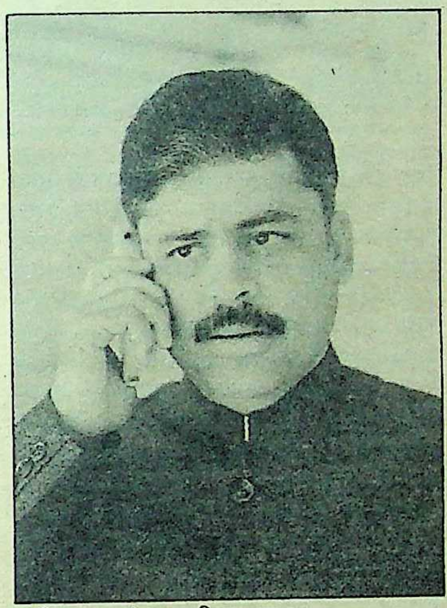

बड़ी महत्वाकांक्षा : तारिक अनवर

भ्रम : दरअसल, मध्यप्रदेश के उदाहरण ने बिहार राजनीतिज्ञों के गणित को गड़बड़ कर दिया। केंद्रीय मंत्री बिंदेश्वरी दुबे इस समीकरण में उलझ गये कि मोतीलाल वोरा अगर फिर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो बिहार में उनकी गोट दोबारा क्यों नहीं जम सकती ? इसी चक्कर में दुबे की भारी फजीहत भी हुई और उन्हें सख्त हिदायत दे दी गयी कि ऐसे सपने वे कतई न देखा करें। तारिक अनवर भी इसी तरह गच्चा खा गये। ११ मार्च को जब बिहार में नये मुख्यमंत्री के चुनाव की औपचारिकता पूरी करने दिल्ली से पर्यवेक्षकों की टीम पटना के लिए रवाना हो रही थी, उसी समय केंद्रीय राज्यमंत्री शीला दीक्षित ने तारिक अनवर को उनके २०, इंदिरा गांधी मार्ग स्थित दिल्ली निवास पर फोन कर कहा कि पर्यवेक्षकों के साथ उन्हें भी जाना है, जबकि सत्येंद्र नारायण सिंह पर्यवेक्षकों के साथ नहीं, बल्कि बाद में जाने वाले थे। लिहाजा, तारिक को स्वाभाविक रूप से यह लगा कि जिस तरह मध्यप्रदेश में माधव राव सिंधिया के नाम पर विधायकों के विद्रोह करने के बाद अंत में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने मोतीलाल वोरा का नाम प्रस्तावित कर विवश हो बीच का रास्ता निकाला था, उसी तरह अगर पटना में सत्येंद्र नारायण सिंह के नाम पर विधायक राजी नहीं हुए, तो विकल्प के रूप में पर्यवेक्षक उनका नाम पेश कर देंगे। बिहारी नेताओं में एकमात्र उन्हें ही पर्यवेक्षकों के साथ जाने का हुक्म हुआ था, इसलिए और कोई दूसरी बात सोची भी नहीं जा सकती थी। वैसे भी, दिल्ली दरबार के गलियारे में यह अस्फुट चर्चा थी कि सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम तो पहले नंबर पर है ही, लेकिन एक-दो वैकल्पिक नाम भी पर्यवेक्षकों को यह कहकर बताये गये हैं कि इन नामों को एकदम गुप्त रखें और अगरचे विधायक पहले नंबरवाले नाम पर अड़ें, तो वैकल्पिक नाम पर सहमति लेने की वे सब कोशिश करेंगे। एक अटकल यह भी थी कि इस बार बिहार में उपमुख्यमंत्री का भी एक पद होगा। बहरहाल इन्हीं तमाम सुखद संभावनाओं के साथ तारिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ पटना के लिए उड़ान भरनेवाले विमान पर जा बैठे। पर विमान में ही भजन लाल ने जब तारिक से यह कहा कि उन्हें

सत्येंद्र नारायण सिंह की सरकार में मंत्री पद के लिए शपथ लेनी होगी, तो तारिक बिलकुल हतप्रभ रह गये। भजनलाल से उन्होंने कहा कि शपथ लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक बार उसके पहले वे आलाकमान से बात करना चाहेंगे। तारिक ने विमान में ही भजनलाल से विनती की कि किसी तरह आज शाम बिहार मंत्रिमंडल में उनका शपथग्रहण वे टलवा दें। बिहार राजनीति के एक दिग्गज खिलाड़ी 'माया' से कहते भी हैं, "तारिक को पता नहीं राजनीति की कोई समझ है भी, या नहीं। पटना में भी लोगों को पता चला कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ तारिक भी आ रहे हैं, तो सबको यह समझते देर नहीं लगी कि तारिक को मंत्री के रूप में शपथ दिलायी जायेगी।" दरअसल, बिहार मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्यमंत्री रफीक आलम और तारिक अनवर में से किसी एक को ऐडजस्ट करने की बात थी, क्योंकि एक साथ दोनों को केंद्र में रखना कठिन था। आखिरकार दिल्ली दरबार में तय हुआ कि तारिक को ही पटना में ऐडजस्ट कर दिया जाये।

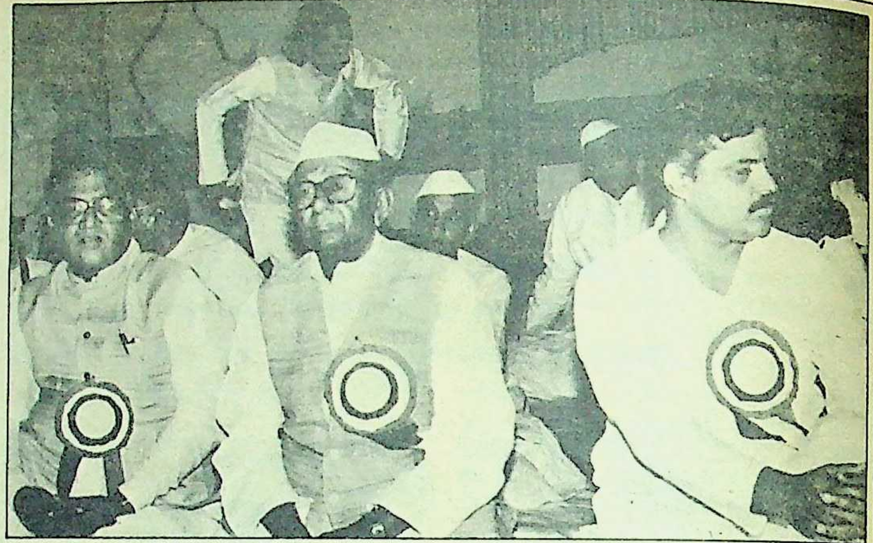

जगन्नाथ और केसरी से रुष्ट : बायें से डा० जगन्नाथ मिश्र, सीताराम केसरी एवं तारिक अनवर

भजनलाल असमंजस में थे। एक तरफ बिमान के पटना उतरने के पहले तक बेचैन मिन्नत करते तारिक अनवर सामने थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली दरबार से तारिक के बारे में मिला दो टूक निर्देश उन्हें परेशान कर रहा था। अपने मन से फैसला लेने में वे हिचक रहे थे। बहरहाल, विमान में भजनलाल तारिक को कोई आश्वासन नहीं दे सके। उसी दोपहर जब पटना में सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के लिए स्वीकार कर लिया गया, तो फिर मंत्रिमंडल की सूची तैयार करने की अफरातफरी मची। भजनलाल को तारिक के बारे में आलाकमान का आदेश बार-बार कुरेद रहा था। सो सदाकत आश्रम में फिर भजनलाल ने तारिक से कहा कि वे शपथ ले लें, फिर आलाकमान से बात कर लेंगे। सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र ने भी तारिक से कहा कि आलाकमान की मरजी को वे नजरअंदाज न करें। पर तारिक ने सदाकत आश्रम में अलग से भजनलाल से अंतिम रूप से कातर अनुरोध किया कि बस आजभर उनका शपथ ग्रहण न करवाया जाये। भजनलाल विवश होकर मान गये। लिहाजा, तारिक की बेचैनी कुछ शांत हुई। शपथग्रहण समारोह में शामिल होने तमाम नेता राजभवन पहुंचे। शपथग्रहण के पूर्व राजभवन की ऊपरी मंजिल में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ सत्येंद्र नारायण सिंह, डा० जगन्नाथ मिश्र आदि मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम रूप दे रहे थे। इसी दौरान जगन्नाथ मिश्र ने तारिक का मामला उठाया कि जब आलाकमान की खास हिदायत है कि तारिक अनवर मंत्रिमंडल में शामिल हों, तो इसे कैसे टाला जा सकता है? भजनलाल से जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि आप आलाकमान के फैसले को पटना में कैसे बदल देंगे? भजनलाल इस मसले पर असमंजस में शुरू से ही थे, सो जगन्नाथ मिश्र के जोरदार तर्क के आगे वे खामोश रह गये। सत्येंद्र नारायण सिंह इस वाद-विवाद में चुप ही थे, क्योंकि आलाकमान के निर्देश में किसी किस्म का संशोधन या सुझाव वे नहीं देना चाहते थे। इस तरह उस शाम, राजभवन की ऊपरी मंजिल में अंतिम रूप से तैयार मंत्रिमंडल की सूची के सबसे अंतिम नंबर पर तारिक अनवर का नाम जोड़ दिया गया। पर राजभवन में जब सबसे अंत में शपथ के लिए तारिक का नाम पुकारा गया, तो तारिक ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। इस तरह यह जाहिर हो गया कि शपथ न लेकर तारिक ने राजभवन में ही असंतोष की शपथ ले ली। पर ऐसा नहीं कि तारिक की रंजिश सत्येंद्र नारायण सिंह से थी। तारिक तो प्रदेश इंका अध्यक्ष डा० जगन्नाथ मिश्र पर कुपित थे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उनकी कुरसी पर काबिज होने के बाद जगन्नाथ मिश्र ने उनका कद छोटा करने की मुहिम छेड़ दी थी। इसलिए ११ मार्च की रात ही तारिक समर्थकों ने उत्तेजित मुद्रा में कई जगह कहा कि डा० जगन्नाथ मिश्र ने तारिक अनवर के साथ दगा किया है। बिंदेश्वरी दुबे जिन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जगन्नाथ मिश्र से उनकी भीषण लड़ाई चल रही थी, उसी समय से तारिक अनवर दिल्ली दरबार में जगन्नाथ मिश्र की वफादारी कर रहे थे। उन दिनों तारिक सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तारिक अनवर के जगन्नाथ-प्रेम से तारिक के गुरु सीताराम केसरी भी क्षुब्ध थे, क्योंकि केसरी व जगन्नाथ के रिश्ते हरदम कटु रहे हैं। तारिक जब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आये और जब अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद से उनकी लड़ाई चल रही थी, उस दौरान भी तारिक दिल्ली दरबार में जगन्नाथ मिश्र के लिए यह कहकर लाबी कर रहे थे कि बिहार में ठोस जनाधार वाले इस नेता को और अधिक प्रताड़ित न कर पुनर्वासित किया जाये। तारिक के एक निकटवर्ती का कहना है कि जगन्नाथ मिश्र जब कभी दिल्ली में होते थे, तो आधे से अधिक वक्त उनका तारिक के साथ गुजरता था और तारिक जब पटना में अपने दफ्तर, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होते थे, तो भी जगन्नाथ मिश्र उनके पास अलख जगाया करते थे। जगन्नाथ मिश्र जैसी राजनीतिक हस्ती को अपने सामने दंडवत की मुद्रा में खड़े देख तारिक गलतफहमियों के शिकार हो गये थे कि वाकई कांग्रेस का यह बेकाबू नेता उनके काबू में आ चुका है। बिहार राजनीति के एक महीन खिलाड़ी 'माया' से कहते हैं, "जगन्नाथ मिश्र के साथ आखिर तारिक ने राजनीतिक गोट जमाने की बात सोची भी कैसे? तारिक जबकि स्वयं मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे। ऐसी स्थिति में उस जगन्नाथ मिश्र से उसकी कैसे निभती जो मुख्यमंत्रित्व से हटने के बाद केवल इसी बात को लेकर आलाकमान तक से लड़ रहा है कि उनकी खोयी गद्दी वापस की जाये। एक ही पद के दावेदार दो महत्वाकांक्षी कैसे एक दूसरे पर एतबार करने को राजी होते? बेशक यह तारिक की अनुभवहीनता थी।"

दिल्ली की नाराजगी: क्या बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्देश देकर दिल्ली दरबार ने तारिक अनवर के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया? हालांकि तारिक ने इस विवाद के बाद बयान जारी कर कहा कि उन्हें बिहार मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्देश आलाकमान ने किसी को नहीं दिया था। यह तो कुछ स्थानीय नेताओं की उनके खिलाफ एक गंदी चाल थी। तारिक का इशारा स्पष्ट रूप से जगन्नाथ मिश्र की तरफ था। बिहार के एक पूर्व मंत्री 'माया' से कटाक्षपूर्वक कहते हैं, "पौराणिक आख्यानों में जिस तरह किसी यक्ष को दंडित कर पृथ्वी पर रहने के लिए भेजने का प्रसंग आता है, ठीक उसी तरह अरसे से राष्ट्रीय राजनीति के इस सितारे को दंडित कर पटना की राजनीति में रहने को कहा गया था।" सचमुच दिल्ली दरबार ने तारिक को यह दड ही दिया था। भागवत झा आजाद विरोधी मुहिम में

माफिया से बचकर रहना : पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद वर्तमान मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ

जब तारिक भी जोर-शोर से शरीक हुए, तभी आलाकमान ने उन्हें सचेत किया था, पर उस समय तारिक आलामान के रुख को ठीक से भाप नहीं सके। २० सूत्री कमेटी की अध्यक्षता से जब तारिक ने आजाद का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया था, उसी समय राजीव गांधी ने उनसे कहा था, "तारिक, तुम्हें तो मैंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बिहार भेजा था, विक्षुब्ध राजनीति के लिए नहीं। विक्षुब्ध राजनीति के लिए तो वहां पहले से बहुत लोग हैं।" पर तारिक राजीव गांधी की इस टिप्पणी में छिपे गुस्से को नहीं समझ सके। जो तारिक दिल्ली में रहकर यह अच्छी तरह समझते थे कि विक्षुब्ध राजनीति करनेवाला नेता कभी सत्ता का शीर्ष पद नहीं हासिल कर पाता, वही तारिक पटना में आकर इस बात को भूल गये। उन्हें लगा कि आजाद की कड़ी मुखालफत कर वे आजाद की जगह काबिज होने में कामयाब हो जायेंगे। फिर डा० जगन्नाथ मिश्र और रामाश्रय प्रसाद सिंह सरीखे महीन खिलाड़ियों ने भी उनकी महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित कर दिया था। नतीजतन तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष शिवचंद्र झा के बाद यह तारिक ही थे, जो भागवत झा आजाद के खिलाफ झंडा पकड़कर उठ खड़े हुए। फिर जब आजाद के खिलाफ भीषण बवंडर जनवरी के अंतिम सप्ताह में तैयार हुआ, तो उसमें भी तारिक की सक्रिय भूमिका थी। चार सदस्यीय शांति मिशन में भी जब उन्हें शरीक किया गया, तो वे इस उम्मीद में थे कि बिहार में अल्पसंख्यक व युवा मुख्यमंत्री के नारे के तहत उन्हें आजाद का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। तारिक की यह महत्वाकांक्षा गलत भी नहीं थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में वे बिहार से लेकर केंद्रीय स्तर तक कांग्रेस संगठन में बिना किसी संघर्ष या श्रम के महत्वपूर्ण ओहदे पाते रहे। बिहार राजनीति के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ 'माया' से कहते भी हैं, "जिस लड़के को बिना पसीना बहाये लगातार महत्वपूर्ण पद मिलता गया, उसकी महत्वाकांक्षा भला कैसे नहीं अमर्यादित होती?"

अतीत : १९७४ में पटना शहर के पीरबहोर थाने के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मनोनीत तारिक अनवर इतनी अल्प अवधि में कांग्रेसी राजनीति के शिखर पर कैसे आये, इसकी लंबी कथा है। १९७४ के उन दिनों में पटना नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, गौरी शंकर सिंह। गौरी शंकर ने तारिक अनवर को पीरबहोर थाना कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया था। पटना के सब्जीबाग मुहल्ले में रहनेवाले इस लड़के के पिता काफी पहले राजनीति में रह चुके थे। तारिक के दादा की भी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बहरहाल, तारिक पीरबहोर थाने की राजनीति में जुट गये।

उन दिनों बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, अम्बिका प्रसाद और महामंत्री थे ज्ञानरंजन। ज्ञानरंजन ने तारिक को प्रदेश युवक कांग्रेस में सचिव नियुक्त करवा दिया। लिहाजा, तारिक सदाकत आश्रम बराबर आने-जाने लगे। उन दिनों सीताराम केसरी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। केसरी ने तारिक को काफी प्रोत्साहित किया। केसरी को शायद लगा कि यह शांत और अंतर्मुखी लड़का काफी आगे निकल सकता है। बहरहाल, अम्बिका प्रसाद जब अध्यक्ष पद से हटे, तो युवक कांग्रेस के नये प्रांतीय अध्यक्ष के चयन के लिए बतौर पर्यवेक्षक युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव पंकज बनर्जी पटना आये। उस समय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बिका सोनी थीं। बिहार युवक कांग्रेस अध्यक्ष पद के दो दावेदार थे, एक तो ज्ञानरंजन और दूसरे कुमुदरंजन, जो डा० जगन्नाथ मिश्र खेमे के प्रत्याशी थे। पर्यवेक्षक पंकज बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट में ज्ञानरंजन व कुमुदरंजन का नाम अम्बिका सोनी को दिया। अध्यक्ष पद की दौड़ में तारिक का कोई नामोनिशान तक नहीं था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तारिक भी युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। पर सीताराम केसरी ने काफी गोपनीय ढंग से मुहिम चलाकर तारिक अनवर को जब अध्यक्ष बनवा दिया, तो सब सकते में आ गये। इस तरह एक-डेढ़ वर्ष में ही पीरबहोर थाने की राजनीति से प्रदेश अध्यक्ष पद की ऊंची छलांग तारिक ने लगायी। उस समय तारिक को अध्यक्ष बनाये जाने के कारण नाराज कुमुदरंजन ने सीताराम केसरी को आड़े हाथों लिया था।

फिर १९७७ में संसदीय चुनाव आया। केसरी ने कटिहार संसदीय सीट से तारिक को टिकट दिलवा दिया। किसी समय केसरी कटिहार से सांसद थे, पर बाद में वे हार गये थे। सो कटिहार सीट पर अपना हक जताकर उन्होंने अपने शिष्य तारिक को कटिहार से लड़वा दिया। पर १९७७ के चुनाव गें सभी कांग्रेस उम्मीदवारों का सफाया हो गया, सो तारिक भी संसद का मुंह न देख सके। कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी हार के बाद युवक कांग्रेस को देश स्तर पर समाप्त किये जाने की घोषणा कर दी गयी। लिहाजा, तारिक का भी बिहार युवक कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वतः चला गया। पर इसके तुरंत बाद रामचंद्र रथ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर 'कांग्रेस यूथ फोरम' का गठन हुआ और इसमें तारिक राष्ट्रीय महासचिव बनाये गये। फिर जब कांग्रेस-इ का गठन हुआ, तो युवा इंका का भी नये सिरे से गठन हुआ और रामचंद्र रथ युवा इंका के अध्यक्ष बनाये गये। तारिक को फिर बिहार युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। दरअसल, राजनीतिक तिकड़मों के लिए तारिक को स्वयं कभी मगजमारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सीताराम केसरी ही उनके उस्ताद थे। इसलिए तारिक के लिए सारे तिकड़म केसरी ही किया करते थे।

१९८० में कांग्रेस सरकार की वापसी हुई। तारिक इस बार फिर कटिहार से संसद के लिए लड़े और इस बार उन्हें संसद में घुसने का मौका मिल गया। इस तरह सांसद होने के साथ-साथ तारिक बिहार युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बने रहे। पर इसी बीच तारिक को बिहार युवा कांग्रेस की राजनीति में अपने पुराने विरोधी चंदन बागची से जबर्दस्त धक्का लगा। दरअसल, बागची ने तत्कालीन ताकतवर केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी की खूंट थाम रखी थी। सो, एक दिन अचानक प्रणब मुखर्जी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में तारिक को बिहार युवा कांग्रेस-इ के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव कर दिया और चंदन बागची को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करवा दिया। यह निर्णय श्रीमती गांधी के समक्ष हुआ था, इसलिए अपने शिष्य के घायल हो जाने के बावजूद केसरी मन मसोस कर रह गये, पर केसरी बैठे नहीं रहे। उन्होंने मुहिम चलाकर तारिक को कांग्रेस का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त करवा दिया। इसके बाद तो तारिक राष्ट्रीय राजनीति की चोटी पर तेजी से चढ़ते चले गये।

इसके कुछ ही दिनों बाद तारिक को युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। युवक कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से तारिक का संबंध अपने गुरु सीताराम केसरी से ठंडा पड़ने लगा। दरअसल, तारिक को लगा कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में 'स्वतंत्र इमेज' बनानी है और यह केसरी के 'केयर आफ' में रहकर नहीं हो सकता। केसरी भी अपने शिष्य की तेज रफ्तार से सशंकित हो उठे थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि दिल्ली दरबार में तारिक की सीधे पहुंच बन रही थी। पर केसरी-तारिक का यह तनाव सतह पर नहीं आया था। ऊपर-ऊपर दोनों गुरु-शिष्य सद्भाव का नाटक करते रहे थे। केसरी ने तारिक को झटका देने के लिए बिहार की युवा राजनीति में श्याम सुंदर धीरज को शह देना शुरू किया, जो उस समय भी बिहार युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। केसरी के प्रोत्साहन पर धीरज ने तारिक के खिलाफ हल्ला बोल दिया। तारिक के लिए यह स्थिति बेहद मारक थी, क्योंकि वे युवा इंका के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके लिए यह तौहीन की बात थी कि उनके गृह-प्रवेश का अध्यक्ष उन्हें कुछ नहीं समझ रहा था। तारिक ने धीरज को कई बार अध्यक्ष पद से हटाने की पुरजोर कोशिश की, पर केसरी ने दिल्ली दरबार में सीधे लाबी कर धीरज पर तारिक को वार करने से रोक दिया। इस तरह तारिक तड़फड़ाते रहे और गुरु केसरी का यह तर्क उन्हें विचलित करता रहा कि राष्ट्रीय राजनीति में तारिक भले ही चमक लें, पर अपने प्रांत में ही उनकी कोई वकत नहीं। इस तरह धीरे-धीरे केसरी व तारिक का विवाद घनघोर होता गया।

तारिक केसरी के शिष्य तो थे, पर केसरी से उन्होंने पूरी विद्या नहीं सीखी थी, इसलिए केसरी का तिकड़म अब उन्हें तबाह कर रहा था। इसी बीच अर्जुन सिह जब पूरी ताकत से लैस होकर बतौर कांग्रेस उपाध्यक्ष दिल्ली के २४ अकबर रोड में आये, तो गुरु केसरी से परेशान तारिक अर्जुन कैम्प में घुस गये। अर्जुन सिह और केसरी में जब घमासान युद्ध हो रहा था, तो तारिक अर्जुन सिह के साथ थे। इसी बीच तारिक सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आ गये। यह पहला मौका था, जब बगैर अपने गुरु केसरी की मदद से उन्होंने यह पद हासिल किया था। राज्यसभा चुनाव में जब अर्जुन सिह लाबी केसरी का टिकट कटवाने के अभियान में जुटी थी, तो तारिक भी उसमें सक्रिय थे। आखिरकार उस बार केसरी का राज्यसभा से पत्ता साफ भी हो गया और इसके साथ ही केसरी से तारिक का बचा खुचा संबंध भी।

मार्च १९८८ में, जब तारिक बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गये, उस समय भी केसरी ने तारिक की नियुक्ति का जमकर विरोध किया था। पर शायद तारिक केसरी की थोड़ी बहुत काट सीख चुके थे और इसलिए अब केसरी का हर वार खाली जा रहा था। पर नाराज केसरी लगातार कहते रहे कि जिस लड़के को मैंने पीरबहोर थाने की राजनीति से उठाकर देश की राजनीति में ला दिया, उसे मैं ही फिर वापस पीरबहोर थाने की राजनीति में भेजूंगा। केसरी को जगन्नाथ मिश्र से खुंदक रहती थी, इसलिए तारिक ने जगन्नाथ मिश्र से संबंध बनाया। बहरहाल, तारिक ने तो महज केसरी को चिढ़ाने के लिए जगन्नाथ मिश्र से रिश्ते कायम किये, पर यह बात आलाकमान को अखर गयी। बिहार के एक माहिर राजनीतिज्ञ मजा लेते हुए कहते हैं, "तारिक अनवर ने ही सबसे ज्यादा जगन्नाथ मिश्र की वकालत राजीव गांधी से की थी, इसलिए दंडस्वरूप उन्हीं की कुरसी पर जगन्नाथ मिश्र को आलाकमान ने पुनर्वास दे दिया।"

पर जिस तारिक ने जगन्नाथ मिश्र की इतनी जोरदार मदद की थी, वही तारिक अब इस बात से क्यों दग्ध हैं कि जगन्नाथ मिश्र ने साजिश कर उनको बिहार में मंत्री पद का प्रस्ताव दिलवा दिया?

तारिक

जिस ढलान से फिसले हैं, इससे इतनी जल्दी उठकर आना आसान नहीं है।

तारिक के शुभचिंतकों का कहना है कि कम दिनों में ही तारिक अनवर ने बिहार के मुसलमानों मेंअपनी अच्छी खासी पैठ बना ली थी और जगन्नाथ मिश्र को इसी बात से परेशानी हो रही थी। जगन्नाथ मिश्र बिहार में मुस्लिम वोट पर कमांड रखने का दावा करते रहे थे, क्योंकि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में मिश्र ने उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया था, पर तारिक की सक्रियता से जगन्नाथ मिश्र के मुकुट में लगी अल्पसंख्यक शक्ति की कलगी पर संकट आ सकता था। इसलिए जगन्नाथ मिश्र ने अपने खेमे के एचएच रहमान, जो पहली बार ही विधायक बने थे, को सत्येंद्र नारायण सिह की सरकार में काबीना मंत्री बनवाया और तारिक को यह एहसास करा दिया कि भले ही वे राष्ट्रीय राजनीति के पिच पर बल्लेबाजी करते रहे हों, पर वे पहली बार विधायक बने एचएच रहमान की श्रेणी के ही हैं। भीतरी जानकारों का कहना है कि तारिक को बिहार में मंत्री बनाये जाने का फार्मूला जगन्नाथ मिश्र ने राजीव गांधी को यह कहते हुए सुझाया कि तारिक बिहार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपना 'बेस' बना रहे थे, इसलिए कुछ वर्षों के लिए उन्हें बिहार में ही बतौर मंत्री रहने दिया जाये। राजीव गांधी को भी यह बात जंच गयी कि ठीक है तारिक कुछ दिन अभिशाप भोगें। बहरहाल १२ मार्च को तारिक अनवर दिल्ली गये, ताकि प्रधानमंत्री से मिलकर वे अपना दुखड़ा रो सकें। पर जिस तारिक को फौरन समय मिल जाता था, उन्हें इस बार लगातार कोशिश के बाद समय नहीं मिल सका। जाहिर था, दिल्ली दरबार की भृकुटि तारिक पर तनी थी। वैसे भी पहले से तारिक-विरोधियों ने आलाकमान को सहमत कर रखा था कि वाकई तारिक ने उनके आदेश की अवहेलना की है। बहरहाल, तारिक प्रधानमंत्री के नाम एक विस्तृत पत्र छोड़ कर चले आये। तारिक ने पत्र में लिखा कि वे उनके निकट रहकर संगठन की सेवा करना चाहते हैं और बस सांसद रहकर ही खुश हैं। पटना में तारिक ने बयान देकर कहा कि बिहार में २७ मुस्लिम विधायक हैं, इसलिए मेरे बजाय इनमें से किसी को मंत्री पद पर अवसर दिया जाना चाहिए। दरअसल, मंत्री पद के प्रस्ताव ने तारिक को इसलिए भी भारी संकट में डाल दिया, क्योंकि मंत्री बनने के छह महीने के भीतर उन्हें बिहार विधानपरिषद का सदस्य बनना पड़ता और फिर उनका कटिहार संसदीय क्षेत्र हमेशा के लिए छूट जाता और वर्षों के लिए तारिक पटना की राजनीति में अभिशप्त रहने के लिए बाध्य हो जाते। मार्च के अंतिम सप्ताह में भी उन्हें कुछ लोगों ने राय दी कि वे मंत्री पद स्वीकार लें, इसी में भलाई है। पर तारिक अडिग थे कि जब तक प्रधानमंत्री से वे रूबरू नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल, तारिक 'कौमी तंजीम' नामक अपने संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। तारिक के आलोचकों का कहना है कि ऐसा वे दिल्ली दरबार पर दबाव डालने के लिए करेंगे। वैसे दिल्ली में गुलाम नबी आजाद जैसे तारिक के दोस्त आलाकमान के पास तारिक का बिगड़ा रिकार्ड दुरुस्त कराने की जीतोड़ कोशिश में हैं, ताकि तारिक को केंद्र में मंत्री पद मिल जाये। पर तारिक जिस ढलान से फिसले हैं, इससे इतनी जल्दी उठकर आना आसान नहीं है।

२७ मार्च को जब विधानसभाध्यक्ष पद पर हिदायतुल्ला खान को काबिज कराया गया, तो राजनीतिक पंडितों का तर्क था कि तारिक के गुस्से को 'माइनस' करने के लिए ही आलाकमान ने हिदायतुल्ला को विधानसभाध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। तारिक अगर आज्ञाकारी की भांति मंत्री पद कबूल कर लेते, तो विधानसभाध्यक्ष पद पर किसी पिछड़े या हरिजन को बिठाया जा सकता था। कांग्रेस के एक बुजुर्ग राजनीतिज्ञ कहते हैं, "हिदायतुल्ला को विधानसभाध्यक्ष बनाया जाना तारिक के लिए झटके नहीं तो और क्या है?"

—विकास कुमार झा

कक्काजी कहिन

छुटभैये नेताओं की असली तस्वीर है ?

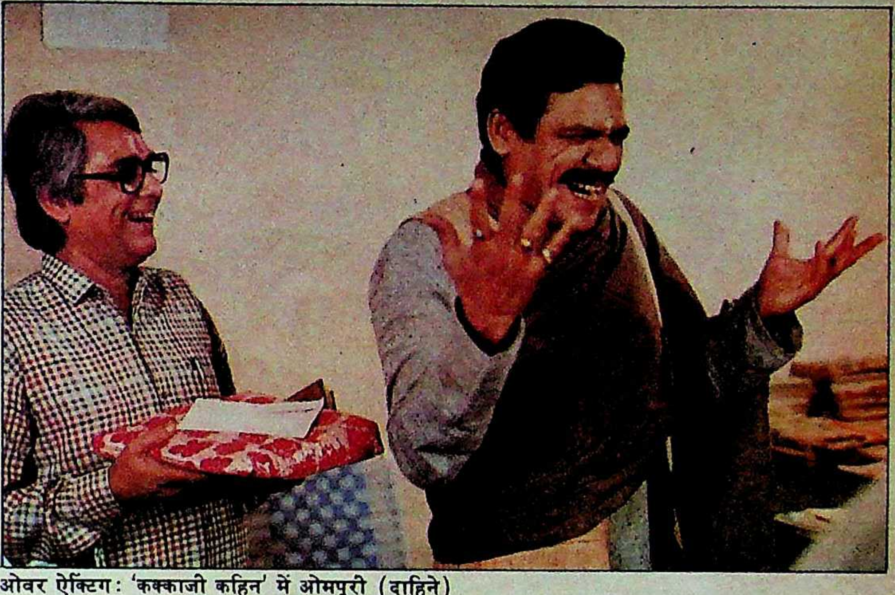

ओवर ऐक्टिंग: 'कक्काजी कहिन' में ओमपुरी (दाहिने)

'कक्काजी कहिन' आज की राजनीतिक-गैरराजनीतिक जिंदगी, माहौल और लोगों की अंदरूनी जिंदगी को कक्काजी के माध्यम से बेनकाब करने की कथा है। कक्काजी प्रख्यात कार्टूनिस्ट लक्ष्मण के टीवी सीरियल 'वागले की दुनिया' के मिस्टर वागले की तरह छिद्रान्वेषित समाज का मूक, लेकिन त्रस्त चरित्र नहीं है, बल्कि इस भ्रष्ट माहौल के सूत्रधारों में से है, उसका प्रमुख अंग है, जो भ्रष्टाचार के नये-नये कारगर तरीके खोजता है और अपना मतलब साधने के लिए नये-नये किरदार तलाशता है, ताकि उनके कंधे पर अपने आर्थिक इजाफे की बंदूक रखकर मुनाफा कमा सके।

'कक्काजी कहिन' बहुत सारे सच और झूठ का सृजन करता है। इसका झूठ उसका काल्पनिक अयथार्थवाद है। बकौल निर्देशक बासु चटर्जी, "कक्काजी जैसे चरित्र हर शहर में पाये जाते हैं जो उनकी तरह अपनी दूकानदारी चलाते हैं और जिंदगी की गाड़ी खींचते हैं, रुपए उगाहने और अपनी अवसरवादिता भुनाने के तरह-तरह के नायाब तरीके ढूंढ़ते रहते हैं।" सीरियल में झूठे व्यामोह की शुरुआत यहीं उनके नायाब तरीकों से होती है, जो दर्शकों का मनोरंजन तो करती है, लेकिन उन्हें ऐसे काल्पनिक इंद्रधनुष के किनारे ला खड़ा करती है जहां उन्हें सच भी झूठ लगने लगता है—कक्काजी और उनके इर्द-गिर्द का माहौल भी अपनी बेबाक सचाई के बावजूद अयथार्थ ज्यादा लगने लगता है—'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' सीरियल की तरह।

'सच'-'झूठ' का अंतर: जब भव्य बहुमंजिली इमारतों के वातानुकूलित केबिनों में बैठकर सामाजिक सचाई पर स्तंभ (पत्रिकाओं के लिए) और पटकथाएं (फिल्मों के लिए) लिखी जाती हैं, तो स्तंभकार और पटकथा लेखक—निर्देशक उस सामाजिक सच के औचित्य से कट जाते हैं और सच कहने की उनकी बुनियादी ईमानदारी और निष्ठा इंद्रजाल सी लगने लगती है। कक्काजी जब एक छोटे-से मुहल्ले या सोसाइटी में समाजसेवा में राजनीति का रंग लाकर एक स्मारक बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और स्मारक के नाम पर कोई भी बेडौल प्रतिमा खड़ी कर देते हैं, तो वह बेनकाब होती हुई सचाई बन जाती है, लेकिन ज्योंही चंदा वसूली में जमा किये ८० हजार रुपए के नोटों से भरी अटैची दिखलाकर 'डकार' जाते हैं, तो वह झूठ का इंद्रजाल बन जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग या दूसरे तरीकों के बावजूद एक छोटे से मुहल्ले या सोसाइटी में इतने रुपए न तो बटोरे और न ही 'डकारे' जा सकते हैं।

'कक्काजी कहिन' के एक प्रसंग में बायें से शैल चतुर्वेदी, सतीश कौशिक और वीना मल्होत्रा

'कक्काजी कहिन' का यह एपीसोड लक्ष्मण के सीरियल 'वागले की दुनिया' के उस एपीसोड की याद दिला देता है जिसमें मुहल्ले के लोग एक संस्था का गठन कर मि० वागले (अंजन श्रीवास्तव) को उसका पदाधिकारी बना देते हैं, कार्पोरेशन का चुनाव लड़ने को उकसाते हैं और अपने घर के सामने जिस कूड़े को हटाने के लिए सामाजिक आंदोलन के तहत लड़ने की वे कोशिश करते हैं, वह जस का-तस बना रहता है। सामाजिक सचाई के भीतर का यह 'झूठ' (भ्रष्टाचार) 'वागले की दुनिया' में अपने आप उद्भाषित हो जाता है, लेकिन 'कक्काजी कहिन' में यही 'सामाजिक सच' एपीसोड के अंत में झूठ लगने लगता है। इसी तरह गजानन बाबू (शैल चतुर्वेदी) के बड़े साले तथा भांजे को फिल्म में हीरो और लेखक तथा दूसरे साले (मयूर) को युवा नेता बनाने, चाचीजी (शिखा दीवान) के भाई को कंप्यूटर ज्योतिषी बनाकर उनकी रोजी-रोटी और कैरियर जमा देने तथा ८० प्रतिशत

साक्षात्कार/**बासु चटर्जी**

‘कक्काजी’ जैसे नेता हमारी राजनीति में आम हैं

माया: मनोहर श्याम जोशी ने इसे ‘नेताजी कहिन’ के नाम से लिखा था, इसे आपने ‘कक्काजी कहिन’ नाम क्यों दे दिया?

बासु चटर्जी: *‘नेताजी’ नाम बहुत कामन हो गया है। इससे कथ्य एवं प्रस्तुतीकरण के प्रति लोगों में भ्रम हो सकता था, इसलिए हमने ‘नेताजी’ की जगह ‘कक्काजी’ कर दिया।*

माया: जोशीजी का ‘नेताजी कहिन’ बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो क्या आपने उन्हीं की लोकप्रियता से प्रभावित होकर सीरियल बनाने का निर्णय किया?

बासु: *मैं उनकी लोकप्रियता के बजाय रचनाधर्मिता से प्रभावित था। जोशीजी की इस रचना को मैं उपन्यास के बजाय ‘रम्य रचना’ कहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैंने दूरदर्शन के तत्कालीन निर्देशक गिल से इस बारे में बात की, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं दूरदर्शन के लिए कोई सीरियल बनाऊं और विषय का चुनाव भी उन्होंने मुझ पर ही डाल दिया था।*

माया: आपने ‘नेताजी कहिन’ के मूल कथ्य में, सीरियल बनाते समय क्या काफी परिवर्तन भी किया है?

बासु: *हां, कई जगह हमें परिवर्तन करने पड़े, व्यंग्य की पैनी धार को कुछ एपीसोडों में हलका बनाना पड़ा। नेताजी कहिन के कुछ हिस्सों पर मंडी हाउस के अधिकारियों को आपत्ति थी।*

माया: किन हिस्सों पर?

बासु: *बहुत से हिस्सों पर।*

माया: लोगों ने इसे पसंद किया, क्या आप ऐसा सोचते हैं?

बासु: *लोगों ने इसे काफी पसंद किया। कक्काजी जैसा चरित्र आम है, हर शहर, हर तबके में मिलता है। लोग ऐसे चतुर, तिकड़मी नेताओं के चरित्र से भलीभांति परिचित हैं।*

माया: ‘कक्काजी कहिन’ का व्यंग्य क्या आम दर्शक समझने में समर्थ है?

बासु: *उसका व्यंग्य ‘ग्रास-रूट’ स्तर का है, अगर लोग इसे नहीं समझेंगे, तो सीरियल उन्हें बेमानी लगेगा। न तो यह कहानी है और न ही इसमें नाटकीय तत्व हैं। यह एक व्यक्ति (कक्काजी) और उसके इर्द-गिर्द घूमते लोगों का रेखाचित्र है।*

माया: आपको नहीं लगता कि ओम पुरी बहुत ‘लाउड’ हो गये हैं।

बासु: *नहीं, यह (लाउडनेस) उनके लिए बहुत जरूरी थी। उन्होंने अपने पात्र को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से निबाहा है। दूसरे कलाकारों ने भी बहुत ही अच्छा अभिनय किया है।*

—दिव्येंदु गुहा

कमीशन अपनी जेब के हवाले करने की कक्काजी की योजना राजनेताओ की दुनिया को बेनकाब तो करती है, लेकिन जिस ‘अंत’ का सृजन लेखक मनोहर श्याम जोशी तथा निर्देशक बासु चटर्जी करते हैं, वह यथार्थ कम, ‘फैंटेसी’ ज्यादा लगने लगता है।

फैंटेसी के नजदीक: ‘कक्काजी कहिन’ अगर फैंटेसी सीरियल होता अथवा इसे ‘फैंटेसी’ की तर्ज में लिखा गया होता, तो बाद दूसरी होती। श्री जोशी ने करारे व्यंग्य के रूप में जो ‘नेताजी कहिन’ लिखा था, उसमें फैंटेसी के बजाय राजनेताओं की जिंदगी, तिकड़मों तथा उनकी दुनिया में पनपनेवाली भ्रष्टाचारनुमा सचाइयों को उजागर करने की उन्होंने ज्यादा कोशिश की थी। जब इस सीरियल के निर्माण की योजना बनी थी, तो इस बात के दावे भी किये गये थे लेकिन सीरियल में वह बात उजागर नहीं हो पाती।

बासु चटर्जी जाने-माने कार्टूनिस्ट रहे हैं, इसीलिए अपनी फिल्मों में हास्य-व्यंग्य की सीमा-रेखा को अलग रखते हुए वे पैने व्यंग्य का सृजन करने में सबसे प्रभावशाली निर्देशक रहे और इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा निर्देशक उन्हें आज तक छू नहीं सका था—न पुरानी पीढ़ी का और न ही नयी पीढ़ी का। लेकिन जब उन्होंने ‘कक्काजी कहिन’ का निर्देशन शुरू किया, तो लगा मनोहर श्याम जोशी जैसे सशक्त लेखक का सहयोग उन्हें अपनी रचनाधर्मिता को पुन: बेबाकी से प्रस्तुत करने में सहायक होगा। मनोहर श्याम जोशी ने ‘हम लोग’ तथा ‘बुनियाद’ लिखकर यह प्रमाणित कर दिया था कि सीरियलों के सशक्त प्रस्तुतीकरण के पीछे सशक्त लेखक का होना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो ‘हम लोग’ जैसे प्रभावशाली सीरियल का निर्देशक (पी कुमार वासुदेव) जब विश्वविख्यात कृतियों पर आधारित ‘अजूबे’ व ‘गणदेवता’ का निर्माण करता है, तो सशक्त पटकथा लेखक के अभाव में उस पर से अपनी पकड़ खो बैठता है।

आम नेता की छवि: बासु चटर्जी के अनुसार, “कक्काजी कोई अजूबा चरित्र नहीं है, हमारे समाज के हर तबके में वह मिलता है—चतुर, तिकड़मबाज, अवसरवादी स्वयंभू नेता जो हर मौके का फायदा उठाना जानता है।” आज का नेता भी यही करता है—कस्बाई राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक ऐसे ‘कक्काजीओं’ से भरी पड़ी है, इसलिए आज ‘राजनीति’ और ‘नेता’ गाली तथा फूहड़ मजाक के पर्याय बन गये हैं। कक्काजी की तरह अधिकांश अवसरबाज नेता शिकार की तलाश में रहते हैं, इसीलिए वे रेत में से भी तेल निकाल लेने की क्षमता रखते हैं।

बासु का ‘कक्काजी’ लक्ष्मण के मि० वागले के मुकाबले बहुत लाउड है। बासु का कहना है, “मैंने जान-बूझकर इस चरित्र को यह ‘मैनेरिज्म’ दिया है—वह अचानक जोर से एक विशेष अंदाज में हंसता है, पान चबाता है।” कक्काजी की भूमिका निभानेवाले ओमपुरी का कहना है, “कक्काजी का यह मैनेरिज्म ही उसकी विशेषता है। मैंने ठीक एक ऐसे ही नेता को बचपन में देखा था। जब बासु दा ने कक्काजी को एक विशेष मैनेरिज्म में ढालने की बात कही, तो मुझे बचपन में देखे उस तथाकथित नेता की याद आ गयी। उसे मैंने विषय के मुताबिक थोड़ा बदला भर है। लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही किया है जैसा बासु दा चाहते थे।”

लेकिन बासु दा तथा ओम पुरी के तमाम दावों के बावजूद उन्होंने कक्काजी को इस हद तक ‘लाउड’ और मेलोड्रैमेटिक बना दिया है कि वह ‘असहनीय’ और ‘थोपा हुआ करेक्टर’ लगने लगता है। एक आम महिला दर्शक (बासु चटर्जी के अनुसार आम दर्शक) जो व्यंग्य और हास्य में ज्यादा अंतर नहीं कर पाता, की प्रतिक्रिया थी—“कक्काजी की भूमिका में ओम पुरी से बेहतर ‘वागले की दुनिया’ वाले अंजन श्रीवास्तव होते। सिर्फ बेमेल ठहाका लगाकर दर्शक को हंसाया नहीं जा सकता। अंजन श्रीवास्तव भी (‘वागले की दुनिया’ में) हंसाते हैं और वे रघुवीर यादव (‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’) तथा ओम पुरी (‘कक्काजी कहिन’) के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावित करते हैं। ओम पुरी से अच्छा अभिनय तो शैल चतुर्वेदी (गजानन बाबू) करते हैं, जैसे प्यारेमोहन सहाय (मुंगेरीलाल के श्वसुर की भूमिका में) ने किया था।”

अगर आम दर्शक प्यारेमोहन सहाय तथा शैल चतुर्वेदी को उनके सशक्त अभिनय के लिए याद रख सकता है, तो बासु दा का तखमीना यहां भी गलत साबित हो जाता है और ‘कक्काजी कहिन’ के एक सशक्त, यादगार सीरियल बनते-बनते रह जाने का जवाब भी मिल जाता है। ओम पुरी और शैल चतुर्वेदी के अलावा, शिखा दीवान को छोड़कर सारे कलाकार निराश करते हैं और कथ्य की मुख्य धारा से अपने को जोड़ नहीं पाते। जानी-मानी माडल शिखा दीवान की भूमिका को अगर पटकथा लेखक का सहारा मिला होता, तो वे अपनी अभिनय क्षमता की छाप छोड़ने में जरूर सफल होतीं।

—रवींद्र श्रीवास्तव

मशहूर जोड़ी : फिल्म 'परिंदा' के एक भावपूर्ण दृश्य में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर

अनिल कपूर

क्या अमिताभ को पीछे छोड़ जायेगा?

पहले एन. चंद्रा की 'तेजाब', फिर सुभाष घई की 'राम लखन' और उसके बाद के विश्वनाथ की 'ईश्वर'—चार महीने के भीतर प्रदर्शित इन चार फिल्मों ने अनिल कपूर की किस्मत ही बदल दी और उन्हें स्टारडम के उस शिखर बिंदु पर ला खड़ा कर दिया है जिससे ठीक एक सीढ़ी ऊपर बाक्स आफिस के चमत्कृत पुरुष अमिताभ बच्चन पिछले डेढ़ दशक से अपना वर्चस्व बनाये खड़े थे। 'विजय' से लेकर 'कसम' तक विविध विषयोंवाली फिल्मों के लगातार पिटते रहने के कारण धुंधला आये अनिल कपूर के कैरियर और अभिनय-क्षमता को इन फिल्मों ने न केवल नये सिरे से स्थापित कर दिया, बल्कि उनके १५ लाख से घटकर १०-१२ लाख तक सिकुड़ आये बाजार भाव में वृद्धि कर ३५ लाख तक पहुंचा दिया। अमिताभ के बाद अनिल कपूर अब सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले दूसरे नंबर के अभिनेता हो गये हैं।

इसे अनिल का नसीब कह सकते हैं कि पूरे वर्ष तक फिल्मों के लगातार असफल होते रहने के बावजूद वर्ष में उनकी कोई-न-कोई एक फिल्म अवश्य चमत्कार दिखला जाती है। यह विजयश्री उन्हें हर वर्ष (१९८३: 'वोह सात दिन', १९८४: 'मशाल', १९८५: 'साहेब', १९८६: 'कर्मा', १९८७: 'मि० इंडिया', १९८८: 'तेजाब' तथा १९८९: 'राम लखन') हासिल होती रही है, जबकि दूसरे सितारों के मुकाबले उनकी सबसे कम फिल्में प्रदर्शित होती रही हैं।

कैरियर की शुरुआत: अनिल के फिल्म कैरियर की शुरुआत हिंदी के बजाय एक तेलगू फिल्म से हुई थी, जिसके निर्देशक थे दक्षिण के बापू। इसके बाद बापू ने उन्हें लेकर एक फिल्म बनायी 'एक बार कहो' जो परदे पर पहुंच कर भी उनके लिए निरर्थक साबित हुई थी। एमएस सथ्यू ने अनिल कपूर एवं शेरोन प्रभाकर को लेकर एक कला फिल्म 'कहां कहां से गुजर गया' उन्हीं दिनों बनायी, जो आज तक सिनेमा हाल का मुंह नहीं देख सकी। यह वह समय था जब स्टार पुत्र बड़ी तेजी से अपने पिताओं द्वारा बनायी गयी फिल्मों तथा ढोलपीटू प्रचार के कारण चर्चा में थे, लेकिन अनिल कपूर को ऐसी विरासत नहीं मिली। वे तो शम्मी कपूर के सचिव रहे सुरिंदर कपूर के बेटे मात्र थे। जब सुरिंदर कपूर ने अपनी फिल्म 'हम पांच' के लिए

बापू को बतौर-निर्देशक लिया, तो अनिल उनके सहायक बन गये। तब अनिल ने अभिनय के बारे में सोचा भी नहीं था। अभिनेता बनने की ललक तो उनके भीतर बापू ने ही पैदा की थी।

अनिल ने 'माया' को बतलाया, "शुरुआत के दिनों में मैंने कसम खा ली थी कि मैं फिल्मों में 'लीड रोल्स' ही करूंगा, दूसरी कोई भूमिका नहीं स्वीकारूंगा, भले ही मुझे काम न मिले। मैं कहानियां (फिल्मों), पटकथाएं लिखूंगा, अथवा व्यवसाय करूंगा-कोई भी व्यवसाय। उसके बाद मैंने काफी संघर्ष किया, लेकिन अपने निर्णय से रत्ती भर भी टस-से-मस नहीं हुआ।"

"नसीर की यह बात कतई गलत है कि मैंने जिंदगी में संघर्ष नहीं किया, इसीलिए मेरी आंखों में वह तड़प या बेचैनी नहीं दिखलायी पड़ती, जो जैकी श्राफ या उनकी आंखों में दीखती है।" उन्हीं दिनों मुझे 'मशाल' में काम मिला। जिस दिन मैंने फिल्म साइन की, उस रात तनाव के कारण मैं सो नहीं सका था—मैं हवा में कुलांचे भर रहा था, उत्साह से मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही थीं और इसका कारण था कि दिलीप साब इस फिल्म में थे।

यह वह समय था जब सनी देवल 'बेताब' में तथा जैकी श्राफ 'हीरो' में काम कर रहे थे। 'बेताब', 'हीरो' तथा 'मशाल' का प्रदर्शन लगभग आसपास ही हुआ था। पहली दो फिल्मों की व्यावसायिक सफलता ने सनी देवल और जैकी श्राफ को रातोरात स्टार बना दिया था, वहीं 'मशाल' उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में ही प्रतिष्ठित कर सकी थी। अनिल बतलाते हैं, "प्रेस तथा लोगों ने मेरे अभिनय की काफी तारीफ की थी। इससे मुझे और भी मेहनत करने की प्रेरणा मिली थी। तभी मैंने तय किया कि मुझे रेसकोर्स के घोड़े की तरह, दायें-बायें या पीछे देखने के बजाय सिर्फ सीधे तेज-से-तेज रफ्तार में विनिंग पोस्ट की तरफ भागना है और अपने लक्ष्य बिंदु तक पहुंच कर ही दम लेना है। भगवान और भाग्य को भी शायद यही मंजूर था और मैंने यही किया।"

अनिल के सामने लक्ष्य-बिंदु तो था, लेकिन वे दूसरे सितारों की तरह अंधाधुंध फिल्में अनुबंधित करने की दौड़ में कभी शामिल नहीं हुए, इसीलिए न तो वे गोविंदा या चंकी पांडे की तरह फिल्मों की भीड़ में गुम हुए और न ही उन्होंने अत्यधिक फिल्में साइन कर लेने के बाद फिल्मों की शूटिंग रद्द करनी शुरू की। अनिल बताते हैं, "मैंने शुरू से ही अपनी फिल्मों का एक कोटा नियत कर रखा था।"

लेकिन इसके बावजूद उनके निर्माताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों में 'रिपीट' नहीं किया सिवाय सुभाष घई ('कर्मा' एवं 'राम-लखन') तथा यश चोपड़ा ('मशाल' तथा 'विजय') के। एन चंद्रा ने 'तेजाब' की अतिशय सफलता के बावजूद अगली फिल्म में सनी देवल को ले लिया।

चमत्कारिक मोड़: 'मि० इंडिया' ने अनिल कपूर के कैरियर को एक चमत्कारिक मोड़ दिया था। तब यह बात दूसरी थी कि श्रीदेवी की चमत्कारिक लोकप्रियता और बाक्स आफिस गारंटी को भुनाने की गरज से 'मि० इंडिया' की कहानी ने पूरी तवज्जह श्रीदेवी पर ही दिया था। तब अनिल कपूर अपने को 'नेगलेक्टेड' (तिरष्कृत)-सा महसूस करते थे सेट पर, इसलिए उन्होंने इसे एक प्रकार की चुनौती मानकर अपने कैरेक्टर को अधिक-से-अधिक संवारने के लिए मेहनत की थी।

'मि० इंडिया' मे मिले आत्मविश्वास के फलस्वरूप उन्होंने न केवल फिल्मों में अपनी भूमिकाओं का चुनाव करना शुरू किया, बल्कि उन फिल्मों की अनुबंध राशि वापस लौटानी शुरू कर दी, जिन्हें संघर्ष के दौरान साइन की थीं। उन्हें लगा कि इन फिल्मों में उनकी भूमिकाएं या तो गैरमहत्वपूर्ण हैं या ऐसी अभिनेत्रियों के साथ हैं, जिनके साथ काम करने से उनकी इमेज को धक्का लगेगा। उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं-निर्देशकों को पुनः शूटिंग कर उनकी भूमिकाओं को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए दबाव डाला।

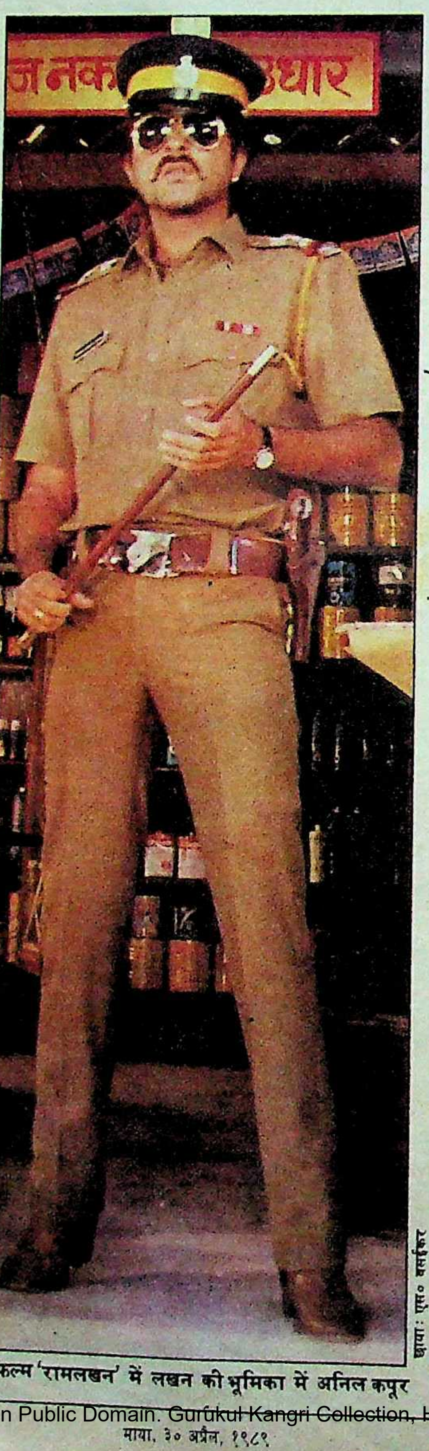

फिल्म 'रामलखन' में लखन की भूमिका में अनिल कपूर

छाया: एस० बसईकर

लेकिन इस सारी सावधानी के बावजूद १९८८ में प्रदर्शित 'सोने पे सुहागा', 'विजय', 'इनकाम', 'कसम', 'राम अवतार' आदि सभी फिल्में एक-एक कर इस तरह पिटीं कि अनिल कपूर का भविष्य पहले की तरह एक बार फिर अंधकारमय दिखलायी पड़ने लगा। बाक्स आफिस तथा फिल्म बाजार में अनिल कपूर की बढ़ रही 'प्राइस' अचानक थम गयी और उसके तेजी से नीचे जाने के आसार दिखलायी पड़ने लगे। लेकिन १९८८ के खतम होते-होते एन चंद्रा की मारधाड़वाली 'तेजाब' अचानक बाक्स आफिस पर अपना चमत्कार दिखला गयी, जिसकी आशा न तो अनिल कपूर को थी, न नायिका माधुरी दीक्षित और निर्माता निर्देशक एन चंद्रा को। 'तेजाब' की सफलता ने उन्हें कुछ इस कदर अभिभूत किया कि अब वे सिर्फ 'कर्मा', 'मि० इंडिया' तथा 'तेजाब' को ही अपनी सर्वोत्तम फिल्में बताते हैं। वे 'माया' से बताते हैं, "इन तीनों फिल्मों की सफलता लाजवाब है। लोग अगले ५०-६० वर्षों तक इन्हें उसी तरह से नहीं भूल पायेंगे जैसे मदर इंडिया, मुगले आजम, आवारा, बरसात, बैजू बावरा, श्री ४२० आदि फिल्मों को नहीं भूल पाते हैं। 'तेजाब' के गाने 'एक दो तीन चार' की तुलना आप भगवान दादा की 'अलबेला' से कर सकते हैं, आज भी जब 'अलबेला' सिनेमाघरों पर लगती है, तो लोगों की भीड़ वहां टूट पड़ती है।"

डायरेक्टर्स एक्टर: अनिल खुद को 'डायरेक्टर्स एक्टर' मानते हैं। उनका कहना है, "फिल्म अच्छी है या बुरी, इसका पता तो उसके प्रदर्शन के बाद ही लगता है, लेकिन मैं अपने को पूरी तरह से निर्देशक के हाथों सौंप देता हूं। कोई भी मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने मेहनत नहीं की या अपने काम में कोताही की। मैं निर्देशक के काम में दखलंदाजी भी नहीं करता।" लेकिन चंकी पांडे अनिल पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 'तेजाब' में उनका रोल कटवाकर एक्स्ट्रानुमा करवा दिया था और एक फिल्म में मार-पीट के सीन में जान-बूझ कर उनकी पिटाई कर दी थी। नसीरुद्दीन शाह को 'परिंदा' से निकलवा दिया था। इन आरोपों का वे जवाब देते हैं, "'तेजाब' में भूमिका मेरी और माधुरी दीक्षित की थी। शूटिंग के समय चंकी के कई सीन ज्यादा फिल्माये गये थे, जो मूल पटकथा तथा कहानी में नहीं थे। बाद में संपादन के समय अगर निर्देशक एवं संपादक ने उन दृश्यों को निकाल दिया,

IF YOU ARE A REGULAR BUYER OF INDIAN MAGAZINES AND NEWSPAPERS, YOU SHOULD READ THIS AD CAREFULLY

The 1989-90 Union Budget has imposed an unprecedented 30% **ad valorem** customs duty on imported glazed newsprint. As a direct consequence of this levy, the price of glazed newsprint—on which the majority of Indian magazines and the colour supplements of Sunday and daily newspapers are printed—has increased with immediate effect by Rs.3,730 a tonne.

How, you may ask, does all this affect the average reader—or advertiser? In two ways:

- There will now be an immediate and steep increase in the price of nearly **all** magazines and newspapers—by as much as 25%—to absorb some of the cost of the unprecedented hike in customs duty.
- There will also be a significant increase in the advertising rates of most newspapers and magazines.

In 1984, when the government last introduced a levy on newsprint (a Rs. 825 per tonne—less than a quarter of the present levy), the newspaper industry approached the Supreme Court on the ground that the levy was **an abridgement of the fundamental right of expression.** The Supreme Court in 1984 recommended that the duty should be reduced to Rs.550/- per tonne and reprimanded the government that the duty was **a tax on communication of knowledge** and that "the government had not taken all relevant aspects into account while levying it."

The publishing industry has already absorbed an increase in the price of newsprint between July 1988 and January 1989 of nearly 50%. The 30% customs duty imposed in the 1989-90 Union Budget on top of this will mean that the price of glazed newsprint will have virtually doubled in 8 months—on unprecedented situation for any industry.

The publishing industry is especially vulnerable because the cost of producing a publication is far greater than its selling price—the difference is made up by advertising revenue. Newspapers and magazines thus solicit and carry advertising to **subsidise** their selling price for the benefit of their readers. (For example, a typical newspaper costs **Rs.5** to produce but sells for only **Rs.1.50** or less).

It is, therefore, in the public interest—quite apart from the fact that the customs levy on newsprint was interpreted by the Supreme Court in 1984 as a tax on knowledge and freedom of expression—that the present levy be immediately rescinded.

The public has a right to receive newspapers and magazines—the only media in India **not** controlled by the government—at prices that are both reasonable and stable.

The government's unprecedented 30% customs levy on imported glazed newsprint (which is not manufactured indigenously) will ensure precisely the reverse: the cost of publications and their advertising rates will now be wholly dependent on the STC's pricing, and the comparative value of the dollar and the rupee.

The publishing industry and its constituents—readers and advertisers—must not let this levy stand. It is not only an impediment to the media, it is against the public interest.

Issued by a group of member-publications of the Indian Newspaper Society (INS)

ध्यान रखिये!
वाहन समान रफ़्तार से ही चलाइये!

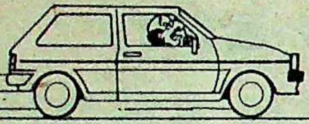

रहें सावधान
हरदम रखें हवा का ध्यान!

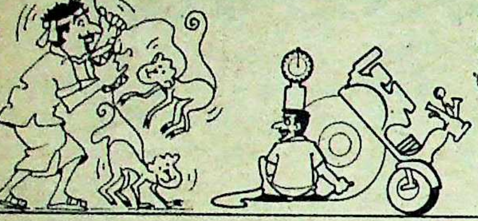

ध्यान दीजिए!
क्लच का सही इस्तेमाल कीजिए!

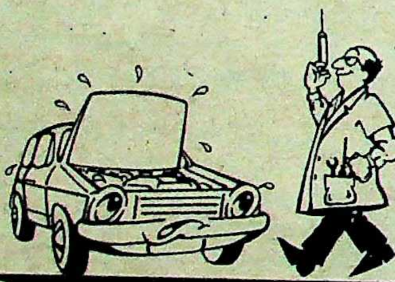

ध्यान रखें एक बात
इंजन रहे ठीक-ठाक!

और हर लीटर में ज़्यादा दूरी तय कीजिए!

आप पैट्रोल का दाम नहीं, इसका खर्च ज़रूर कम कर सकते हैं.
आपके वाहन का ईंधन बचाने के लिए कुछ प्रमाणित उपायों पर अमल करके.
ऐसे उपाये जिनसे हर लीटर में ज़्यादा दूरी तय की जा सकती है.

पैट्रोलियम कन्ज़र्वेशन रिसर्च एसोसिएशन
PCRA
1008, नई दिल्ली हाउस, 27 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001

ULKA-D-PCRA-418 HIN

तो उसमें मेरा क्या कुसूर ! 'परिंदा' में तो नसीर थे ही नहीं, निकलवाने की बात ही भला कहां उठती है उन्हें ? मैं इस तरह की गंदी राजनीति में नहीं पड़ता। हां, किसी सीन में अगर जोर का हाथ चंकी पर पड़ गया हो, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझ कर नहीं किया था। सीन के प्रति ज्यादा इन्वाल्व हो जाने के कारण ऐसा हुआ होगा। रही सनी देवल तथा संजय दत्त की बात, तो वे मेरे मित्र हैं, मैं कैसे मान सकता हूं कि उन्होंने आरोप लगाये होंगे। अगर लगाये भी होंगे, तो किसी गलतफहमी या किसी के बहकावे में आकर।" फिर वे अपनी बात बदल देते हैं, "आप इनकी बातों पर ध्यान मत दें, मैं भी नहीं देता। देता हूं, तो सिर्फ अपनी फिल्म पर।"

इतनी सारी फिल्मों में अभिनय के लिहाज से 'वोह सात दिन', 'तेजाब', 'कर्मा', बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन 'ईश्वर' सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण फिल्म है। उनकी पहचान 'वोह सात दिन' से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक भोले-भाले और मासूम युवक की भूमिका की थी। वे बतलाते हैं, "वोह सात दिन' का नायक 'ईश्वर' से सर्वथा भिन्न था—मासूम होने के बावजूद वह ईश्वर के नायक की तरह 'एबनार्मल' (असामान्य) नहीं था। वह हंसता, नाराज होता तथा जरूरत पड़ने पर लड़ भी लेता था, लेकिन 'ईश्वर' में ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की थी। मैंने शराब पीना, सामिष भोजन तथा दूसरी चीजें उस दौरान छोड़ दी थीं। हां, 'ईश्वर' में काम करने का निर्णय लेने में मुझे लगभग एक वर्ष जरूर लगे थे । इस तरह का कैरेक्टर करने से मेरी स्टार इमेज को धक्का लगने का खतरा था, इसलिए बहुत से लोग मना करते थे। मैंने जब इसके मूल संस्करण ('स्वाथि मुथियम') को देखा, तो इस फिल्म को करने की ललक लग गयी। 'स्वाथि मुथियम' में मेरी वाली भूमिका कमल हासन ने निभायी थी और उन्होंने 'नायकम' तथा 'पुष्पक' से भी अधिक जबर्दस्त अभिनय किया था। पहले राज साहब (स्व० राज कपूर) भी उसे हिंदी में बनाना चाहते थे और नायक की भूमिका के लिए कमल हासन और मैं उनके दिमाग में थे। निर्णय लेने में विलंब इसलिए भी लगा कि इसकी शूटिंग में मैं पूरी तरह से 'इन्वाल्व' होना चाहता था और अधिकांश डेट्स निर्माता (मल्लिकार्जुन राव) को देना चाहता था। फिल्म साइन करने के बाद मैं कई दिन तक जुहू स्थित मानसिक रूप से अपरिपक्व बच्चों के स्कूल में गया। वहां उनके आचार-व्यवहार, तथा बात-चीत के अंदाज को 'आब्जर्व' करता रहा। फिर उसे घर आकर खुद पर दोहराता—शीशे के सामने खड़ा होकर, फिर पत्नी के सामने। इसके बाद उस स्कूल के अध्यापक के सामने भी किया। जब सभी ने ओके कर दिया, तभी सेट पर गया। हां, सेट पर शुरू के दो-तीन दिन जरूर कठिन रहे, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो गया।"

दृश्य की मांग के हिसाब से अभिनय: किमी कातकर और अनिल कपूर फिल्म 'कालाबाजार' में छाया: नेटवर्क

राजकपूर का प्रभाव: अनिल कपूर राजकपूर से बेतरह प्रभावित हैं। उन्होंने 'आवारा', 'जागते रहो', 'जिस देश में गंगा बहती है', 'श्री ४२०.' आदि फिल्मों में अति मासूम भोले-भाले व्यक्ति की भूमिकाएं की थीं, जिसे दुनिया अपरिपक्व और पागल समझती है, 'ईश्वर' के नायक के साथ भी ऐसा ही था। अनिल कपूर 'ईश्वर' की भूमिका में राजकपूर से प्रभावित होने की बात मंजूर करते हैं साथ ही यह भी कहते हैं, "जब कमल हासन ने यही भूमिका 'स्वाथि मुथियम' में की थी, तो उनके शिवाजी गणेशन से प्रभावित होने की भी बात कही गयी थी और एक हद तक यह सही भी था।"

अनिल कपूर सिर्फ स्टार भर बने रहना नहीं चाहते थे। वे अभिनेता भी बनना चाहते थे और इसका प्रमाण उन्होंने 'मशाल' में दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ अभिनय करके प्रमाणित भी कर दिया था। दिलीप कुमार बतलाते हैं, "यश जब मेरे सामने इस लड़के को ले कर आये, तो मुझे इसके मासूम-भोले चेहरे और समंदर जैसी गहरी आंखों के भीतर एक आग-एक तड़प दिखी, जो बिलाशक अभिनय की आग थी जिसे सामने लाने के लिए समय और मौके की उसे जरूरत थी। मैंने उस लड़के से कहा, 'देखो बरखुरदार, जब मेरे सामने शाट देने आना, तो भूल जाना कि मैं दिलीप कुमार हूं, यह भी दिमाग से निकाल देना कि तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा ऐक्टर खड़ा है—मैं सचमुच बहुत बड़ा ऐक्टर नहीं हूं, मामूली ऐक्टर हूं जो हर फिल्म, हर सीन और साथ काम करनेवाले साथी कलाकारों से नयी तालीम लेता हूं। कैमरे के सामने, हम-तुम सिर्फ किरदार होंगे और यह भी ध्यान रखना कि कैमरे की आंख मामूली-से-मामूली बात को भी अपने भीतर अक्स कर लेती है।' और जनाब, उस पहले ही सीन में उस लड़के ने बहुत जबर्दस्त अभिनय किया था। आज भी उसका किया हुआ वह सीन मेरे दिमाग में पूरी तरह से जज्ब है। मैंने उसी दिन रात को उसके वालिद साहब को फोन पर बधाई दी कि उनका साहबजादा यकीनन जहीन आर्टिस्ट है और इसी तरह से मेहनत व पूरी तवज्जह के साथ काम करता रहा, तो माशा अल्लाह वह बहुत बड़ा स्टार-ऐक्टर बनेगा। फिर इसने 'कर्मा' में मेरे साथ काम किया—उसके अभिनय में मेच्योरिटी आने लगी थी। 'ईश्वर' में तो (सुभाष घई की 'राम लखन' में भी) सचमुच उसने हैरतअंगेज काम किया है। एक दिन बतला रहा था कि 'परिंदा' भी इसकी आनेवाली लाजवाब फिल्म है।"

अनिल कपूर की लोकप्रियता तथा फिल्म बाजार में निरंतर बढ़ती मांग से चमत्कृत निर्माता-निर्देशक कनक मिश्रा ने 'माया' को बतलाया, "अनिल को बाल कलाकार के रूप में सबसे पहले मैंने 'नाच उठे संसार' में मौका दिया था—उसने शशि कपूर के बचपन की भूमिका निभायी थी। अनिल के पिता मेरे दोस्त थे और हम दोनों के आफिस आस-पास थे। तब अनिल कभी-कभी वहां आया करता था। उन दिनों मुझे शशि कपूर के बचपन की भूमिका के लिए एक लड़के की जरूरत थी। बस, अचानक एक दिन खयाल आया और उसे चुन लिया। 'सावन को आने दो' के काफी दिनों बाद मैंने जब खुद 'प्यासा सावन' का निर्माण-निर्देशन शुरू किया, तो नायक की भूमिका के लिए अनिल को ही चुना था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे व्यवधान आये कि अरुण गोविल को लेकर फिल्म बनानी पड़ी।

संभव है, कनक मिश्रा जैसे और भी निर्माता हों जिनके पास तब अनिल ने काम के लिए चक्कर लगाये हों और तब उन्हें अनिल के भीतर 'स्टार क्वालिटीज' न दिखी हों। लेकिन अनिल को इसकी परवाह नहीं। वे कहते हैं, "उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, लेकिन जब भी वे बढ़िया कहानी और प्रपोजल लेकर आयेंगे, मुझे अपना रोल पसंद आ जायेगा, मैं जरूर उनकी फिल्मों में काम करूंगा।" शायद यही अनिल के बढ़ते रहने का रहस्य है।

—बंबई ब्यूरो के साथ कृष्णा

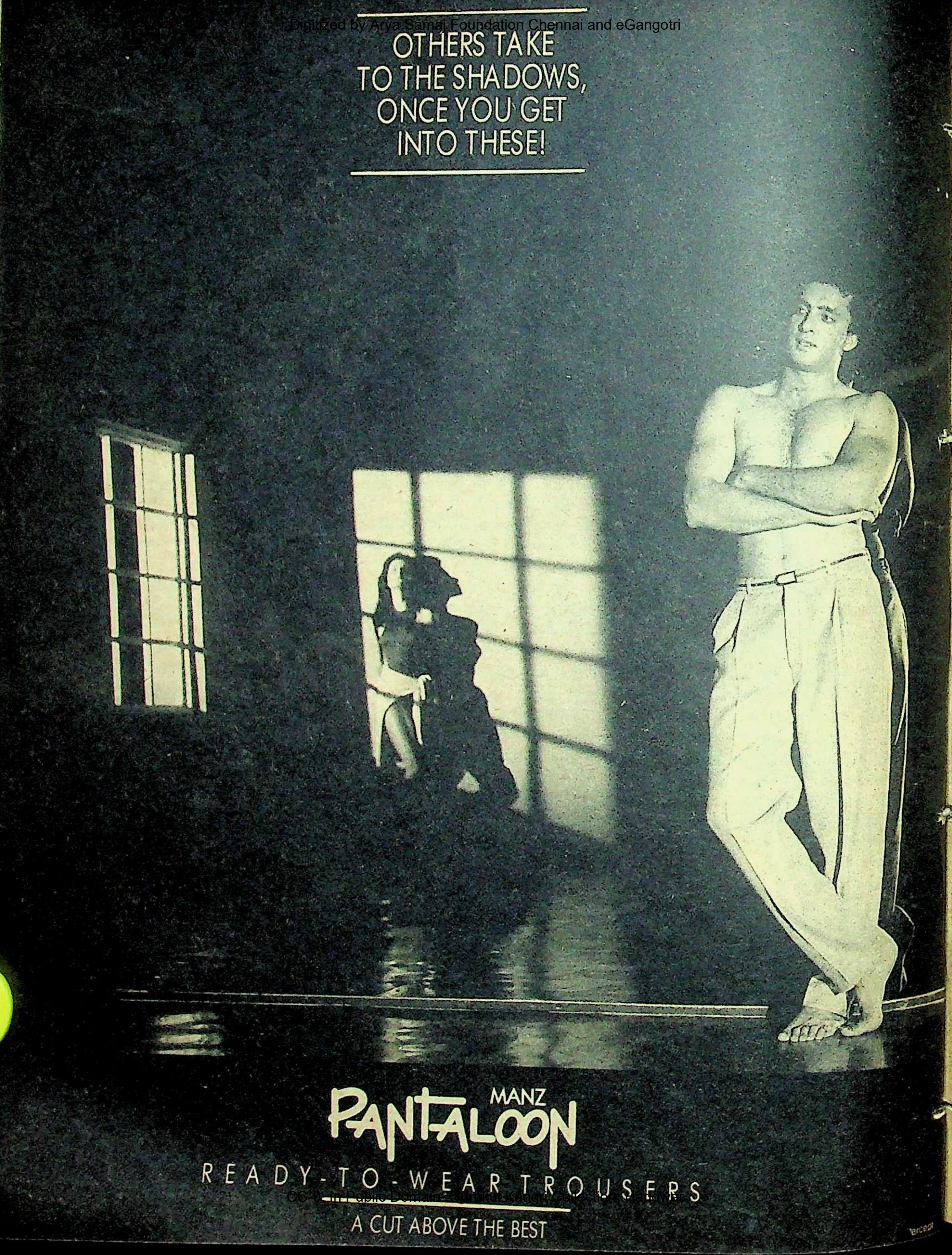
OTHERS TAKE
TO THE SHADOWS,
ONCE YOU GET
INTO THESE!
MANZ
PANTALOON
READY-TO-WEAR TROUSERS
A CUT ABOVE THE BEST

अल्यूमिनियम शेयरों में बढ़त

अल्यूमिनियम तथा सीमेंट उद्योग पिछले माह नियंत्रणमुक्त हो गये। अल्यूमिनियम के मूल्य छह हजार रुपए प्रतिटन अर्थात छह रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गये, जबकि सीमेंट के मूल्यों में संभवत: ६० रुपए प्रतिटन अर्थात तीन रुपए प्रति बोरी की वृद्धि हुई। फलस्वरूप अल्यूमिनियम शेयरों का चढ़ना तथा सीमेंट शेयरों का गिरना स्वाभाविक था।

स्टील की भांति अल्यूमिनियम का भी अधिकांश उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रित है। यही कीमतों के बढ़ते रहने की गारंटी है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी अल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंदुस्तान अल्यूमिनियम के शेयर पिछले दो माह में ५० प्रतिशत चढ़कर, १६० रुपए से (बजट बाद) २४० रुपए हो गये। दूसरी बड़ी अल्यूमिनियम कंपनी इंडियन अल्यूमिनियम के शेयर गत नवंबर में ५० रुपए से बढ़कर बजट के बाद ७५ रुपए हो गये। आशा की जाती है कि अगले चार महीनों में इन शेयरों में ५० प्रतिशत के आसपास की और वृद्धि होगी।

अल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंदुस्तान अल्यूमिनियम के शेयर पिछले दो माह में ५० प्रतिशत चढ़कर, १६० रुपए से (बजट बाद) २४० रुपए हो गये।

कार्बाइड का अंत

यूनियन कार्बाइड के विषय में नवीनतम इतना ही है कि इसका दु:खद भोपाल अध्याय बंद हो चुका है। किंतु आश्चर्य है कि इसके शीर्ष प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रबंध निदेशक वीपी गोखले अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। किंतु कंपनी बढ़िया नहीं जा रही है—इसका व्यापार १९८५ में भोपाल दुर्घटना के समय २४० करोड़ रुपए से घटकर इस वर्ष लगभग २०० करोड़ रुपए पर आ गया। इसके साथ ही लाभ १९८३ के नौ करोड़ रुपए से उतर कर गत वर्ष लगभग दो करोड़ पर पहुंच गया।

भोपाल स्थित इसका कारखाना बंद पड़ा है। यह खुलेगा भी नहीं। कंपनी ने बंबई स्थित अपना नैपथा क्रैकर (भंजक संयंत्र) ओसवाल एग्रोमिल्स के अभय ओसवाल के हाथों ६० करोड़ रुपए में बेच दिया। यह रकम गैस पीड़ितों को ७० करोड़ की क्षतिपूर्ति चुकाने में कार्बाइड के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।

यूनियन कार्बाइड अब अनेक प्रकार के नये उद्योग—कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, डिटरजेंट, तथा कूकिंग रेंज एवं वैक्यूम क्लीनर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की योजना बना रही है, बशर्ते सरकार उसे ऐसा करने की अनुमति दे। हाल ही में कार्बाइड ने महाराष्ट्र में एक रसायन संयंत्र लगाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, किंतु कंपनी के खराब सुरक्षा रिकार्ड के आधार पर सरकार ने आवेदन निरस्त कर दिया।

इसका व्यापार १९८५ में भोपाल दुर्घटना के समय २४० करोड़ रुपए से घटकर २०० करोड़ रुपए पर आ गया। साथ ही लाभ १९८३ के नौ करोड़ रुपए से उतर कर लगभग दो करोड़ पर पहुंच गया।

—डा० जय दुबाशी

Get your
PANTALOON
at:

EAST ZONE

AKASH GANGA, CHASE — Patna, SAPPHIRE — Bhubaneshwar. THE RIGHT SHOP, BROADWAY COLLECTIONS — Shillong. JACKPOT SALES — Imphal. SAMART — Guahati.

WEST ZONE

SIROCCO, KANCHAN DRESS CENTRE, BHARAT WOOLEN HOUSE — Pune. WARDROBE — Nagpur. CORALS — Kolhapur. KOHINOOR CLOTH STORES — Ahmednagar. NEW FASHION CENTRE — Jalgaon. R'AV, EXCLUSIVE, SIDDHARTH, ROMANO, FOLLOW ME — Ahmedabad. SNAP — Rajkot.

SOUTH ZONE

AMIGO — Brigade Road, Bangalore. MENS FAVOURITE SHOP — M.G. Road, Bangalore. MANZ FAVOURITE SHOP — Commercial Street, Bangalore. BINGO — Abid Road, Hyderabad. CHARMS — Koti, Hyderabad. CITIZEN COLLECTIONS — Basheerbagh, Hyderabad. SELECTIONS — Abid Road, Hyderabad. CASH — Swapna Lok, Sec'bad. YAX N YAX — Vijayawada. HANDSOME — Mangalore. AGENCY OLYMPIA — Near Tourist Hotel-Panaji. ASHIRWAD GARMENTS — Shimoga, Karnataka. RED EYE — Cathedral Road, Madras. SINDHUR — Kalpetta. DEETEES — Kalpetta (North). KINGS COURT — Chamundi Complex, Salem.

NORTHERN ZONE

STYLE INN, SARDAR HATTI — Amritsar. SUNIL SELECTION, MODERN GARMENTS, PLEZER, FASHION SHOPPE — Ludhiana. EMM ELL DEPT. STORES — Chandigarh. KHURANA & SONS — Pathankot. BIG BUS, YANK'S INDIA, SURI TRADERS, SELECTION CENTRE — Jammu. DIWANCHAND ATMARAM — Simla. THAKRAL SON'S — Yamuna Nagar. KAYSONS, LAMBA & LAMBA — Lucknow. JINGLE BELLS — Jaipur. FASHION PALACE — Gwalior. LIBAAS-E-HUNAR — Hardwar.

DELHI

A TO Z READY MADES — Kamala Nagar. SUPER GARMENTS — Kamala Nagar. ZENITH TOWN — Karol Baugh. COMAR SONS — Karol Baugh. JAYDEE & SONS PVT. LTD. — Connaught Place. VINTAGE — Connaught Place. CREATIONS — Lajpat Nagar. LUNGANIS — South Extension I. GOGIA'S — Gr. Kailash.

BOMBAY

BULCHAND'S EMPORIUM, GRAND BAZAR— Colaba Causeway. VINOD APPARELS — Kalaghoda. ASIATIC DEPARTMENTAL STORES — Churchgate. CHOOSY — Cuffe Parade. ROOPAM — Crawford Market. TAKE-OFF — Kalbadevi Road. PATLOONS — Charni Road. POSHAQUE — V.P. Road. SEQUEIRA COLLECTIONS — Tardeo. ROOPALI — Kemps Corner. MAYFAIR — Peddar Road. VISHAL BOUTIQUE — Heera Panna, Haji Ali. KANTI STORES — Dadar (W). MILAN STORES, SELECTION CENTRE — Dadar T.T. SHIVOM — Sion Circle. PARISONS, CHOICE CENTRE, CITY BOYS FASHION, TELON, STERLING FASHION, GIMMICKS, ANEES — Bandra. MAYURA BOUTIQUE — Khar (W). GREEN BALL — Juhu-Vile Parle. SHIRTS-N-SLACK — Vile Parle (W). JEMSONS — Irla, Vile Parle (W). SIXER — Santacruz (W). CITY FASHION — Andheri. SAHEEB — Borivli. AKBAR ALI'S — Chembur. IMPRESSION — Mulund. MY SHOPPEE — Mulund. LAIZER — Thane. SAMARAT — Carnac Road. CITIZEN — Malad (E).

MANZ
PANTALOON
Ready-to-wear Trousers

Admn & Sales office
Manz Wear Pvt. Ltd.
G-11, Marol Industrial Area,
M.I.D.C. Marol, Andheri (East).
Bombay 400 093.
Ph: 6345006/6348483.
Delhi Office:
42/4893, Regar Pura,
Karol Baugh, New Delhi-5.

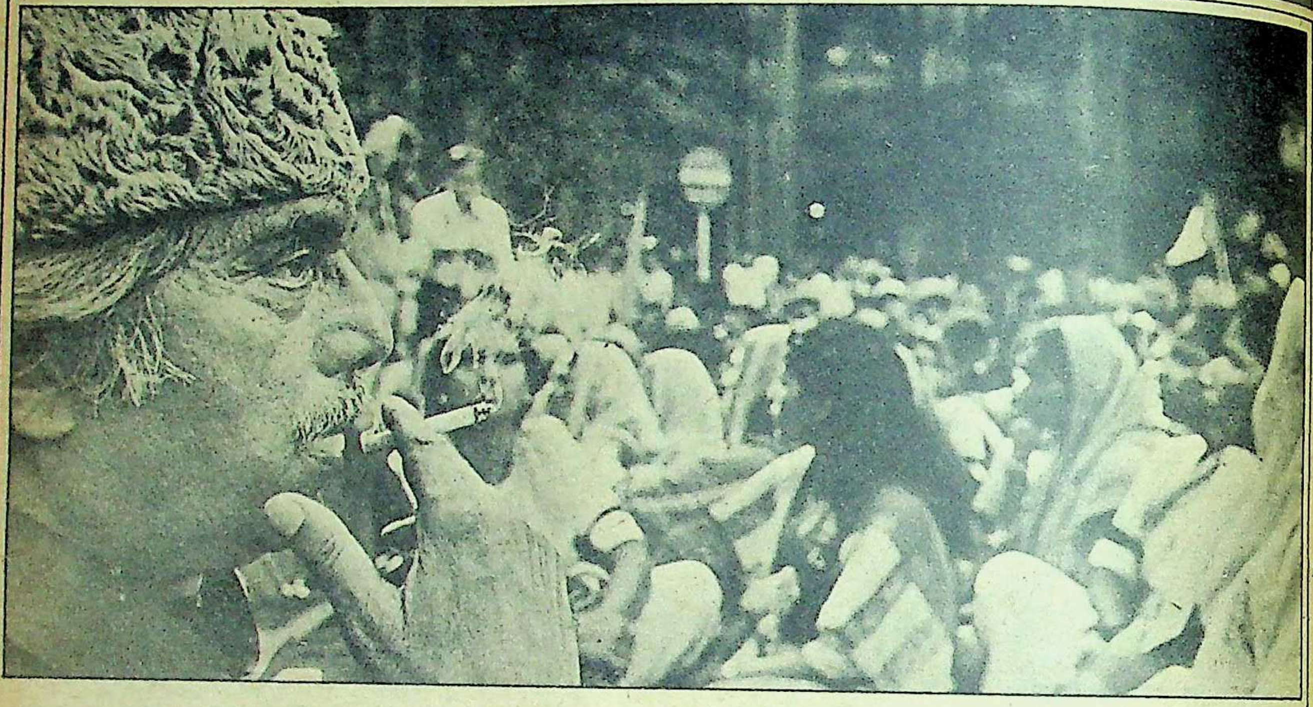

हिंसा की राजनीति और हाजी मस्तान

हाल में सलमान रुश्दी की विवादास्पद पुस्तक 'द सैटेनिक वर्सेज' को लेकर बंबई में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसके पीछे क्या पूर्व माफिया सरगना और अब अपने को अल्पसंख्यकों और दलितों का मसीहा कहनेवाले हाजी मस्तान का हाथ था? यदि नहीं, तो फिर दंगा किसकी शह पर भड़का?

"आपको तड़ीपार क्यो किया गया था?" १८ मार्च के पत्रकार सम्मेलन में एक संवाददाता का यह सवाल सुनते ही हाजी मस्तान का सांवला-सलोना चेहरा एकबारगी सुर्ख हो उठता है। पर दूसरे ही क्षण राजनीतिक मुस्कान बिखेरते हुए वे कह बैठते हैं, "अगर आपने फिर मेरे लिए 'तड़ीपार' लफ्ज का इस्तेमाल किया तो मैं आप पर हतक (मानहानि) का मुकदमा चला सकता हूं। मुझे सिर्फ यहां से चले जाने के लिए कहा गया था। यह हुक्म क्यों दिया गया, इसकी आप शरद पवार से दरियाफ्त कीजिए। वे और पुलिस कमिश्नर बतला सकते हैं कि क्यों वे लोग मुझसे डरते हैं। अगर डरते नहीं होते तो २३ फरवरी की रात में मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेते, क्योंकि २४ फरवरी के जुलूस से न तो हमारे दलित मुस्लिम माइनारिटी सुरक्षा महासंघ का और न ही मेरा कुछ लेना-देना था।"

फार्यारेंग के बाद: इसके बावजूद २४ फरवरी को सलमान रुश्दी के विरोध में आयोजित जुलूस के दौरान १३ लोगों को मौत के घाट उतारनेवाली पुलिस फायरिंग के विरोध में बंबई अमर समिति, बंबई प्रदेश कांग्रेस समिति अल्पसंख्यक सेल, कांग्रेस सेवादल, महाराष्ट्र प्रदेश कौमी तंजीम, बंबई राहत समिति आदि ने मिलकर १८ मार्च,'८९ को तथा हाजी मस्तान के दलित मुस्लिम महासंघ ने २० मार्च को मोर्चा निकाला। (२४ फरवरी को गोलीबारी में मरे १२ मुसलमानों को मस्तान 'शहीद' का दर्जा देते हैं, जबकि १३वां मृतक हिंदू था।) दोनों मोर्चों के नेताओं (जियाउद्दीन बुखारी तथा हाजी मस्तान) ने अपने-अपने मोर्चे में एक-एक लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया था, लेकिन बुखारी के मोर्चे में मुश्किल से ५ हजार तथा मस्तान के मोर्चे में ३ हजार लोग मौजूद थे। बुखारी तथा सहयोगी नेताओं ने गोलीबारी की जिम्मेदारी जहां शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर डाली, वहां मस्तान ने सरकार पर। मस्तान का कहना था, "शरद पवार की सरकार तथा पुलिस कमिश्नर ने जानबूझ कर बेगुनाहों को मरवाया।" बुखारी का कहना था, "पुलिस फायरिंग शरद पवार, गृहमंत्री या पुलिस आयुक्त के हुक्म पर नहीं, बांद्रा (बाल ठाकरे) के इशारे पर हुई थी। उन्होंने बाल ठाकरे के नारे 'गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं' की तर्ज पर 'फख्र से कहो कि हम मुस्लिम हैं' के नारे लगाये। लेकिन मस्तान के मोर्चे में बहुत से लोग अपने मुंह पर काली पट्टियां बांधे हुए थे।

हाजी मस्तान ने 'माया' को बतलाया, "हमारे मोर्चे में भाग लेने के लिए दूर-दूर से ट्रकों, गाड़ियों से तथा पैदल आ रहे स्त्री-पुरुषों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक कर वापस लौटा दिया। कई कार्यकर्ताओं को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।" दलित महासंघ के महासचिव जोगेंद्र कवाड़े ने 'माया' के सवालों के जवाब सवालों में ही दिये, "२४ फरवरी को जब जमावबंदी आदेश था तो लोगों को वहां पर एकत्र होने क्यों दिया गया? अगर उनका (पुलिस का) शक है कि फायरिंग भीड़ से हुई तो उसी समय छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार तथा उनके पास से हथियार बरामद क्यों नहीं किये गये? पुलिस को अगर इस बात का यकीन है कि यह दंगा दलित महासंघ ने कराया है तो वह इसकी न्यायिक जांच क्यों नहीं कराती? आज तक हमने जितने जुलूस निकाले हैं, उनमें कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।"

बंबई और दंगा: समूचे देश में बंबई ही एकमात्र ऐसा महानगर रहा जो अभी तक सांप्रदायिक तनावों से मुक्त क्षेत्र समझा जाता रहा। लेकिन सलमान रुश्दी प्रकरण के बाद बंबई में जो

माहौल बना, वह एक तरफ एक-दूसरे के प्रति अविश्वास तथा नफरत से तो भर ही गया, दूसरी तरफ मुस्लिम नेताओं की रणनीति तथा प्रभाव को लेकर भी प्रश्नचिन्ह उठ खड़े हुए। ऐसे में एक ऐसे मुस्लिम नेता की जरूरत महसूस की जाने लगी, जो बंबई में धन तथा संगठन क्षमता से लैस हो, समूचे मुस्लिम जमात को राष्ट्रीय धारा से जोड़ सके और उनकी रहनुमाई कर सके।

बंबई सांप्रदायिक दंगों की चपेट में, १६३७-३८ के बाद १६८४ में आया। २६ अप्रैल,'८४ को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के एक वक्तव्य के इस अंश को, कि 'मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है', कुछ इस तरह तूल देकर प्रचारित किया गया कि बंबई में शुरू हुए दंगे ने निकटवर्ती ठाणे, भिवंडी, कल्याण आदि को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें लगभग २५० जानें गयीं, तीन हजार घायल तथा १० हजार बेघर हो गये। लेकिन फिर भी आग शांत नहीं हुई। भिवंडी में एक फार्म में २७ लोगों को जिंदा जलाने का हादसा हुआ। फलतः भिवंडी में सेना बुलानी पड़ी। बंबई में मोहम्मद अली रोड पर बम फूटे और दंगाइयों की टोली खुलेआम सड़कों-गलियों में घूमती हुई आतंक मचाती रही।

१६८४-८५ के इस भयावह दंगे के बाद दूसरा दंगा १६८७ के रिलायंस कप सेमीफाइनल में भारत की हार पर एक संप्रदाय द्वारा मिठाइयां बांटने तथा पटाखे छोड़कर खुशियां मनायी जाने के फलस्वरूप हुआ। पुलिस फायरिंग में मारे गये इमरान नामक एक युवक की मौत के खिलाफ निकाला गया जुलूस हिंसक हो उठा और एक पुलिस उपनिरीक्षक बीके परांजपे को छुरा भोंक दिया गया। कई कालोनियों में भीषण आगजनी और लूट-पाट हुई। पुलिस उपायुक्त मुशरिफ के रवैये से क्षुब्ध नागपाड़ा क्षेत्र के २२ गणपति मंडलियों ने अपने-अपने गणपति का विसर्जन करने से इनकार कर दिया। अंततः सरकार को मुशरिफ के कार्यक्षेत्र से नागपाड़ा को अलग करना पड़ा।

तीसरा दंगा २ सितंबर, १६८८ को बोहरा तथा सुन्नी संप्रदायों के बीच हुआ। यह दंगा २८ अगस्त,'८८ को बोहरा धर्मगुरु सैयद द्वारा मुस्लिम खलीफाओं की आलोचना की जाने के कारण हुआ। चौथा दंगा २४ फरवरी '८६ को सलमान रुश्दी की पुस्तक के कारण हुआ, जिसमें १२ व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गये और एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

अपना-अपना मोर्चा: इस बार के विरोध-जुलूस (२४ फरवरी) को लेकर मुस्लिम बिरादरी दो खेमों में बंट गयी है। सलमान रुश्दी की हत्या का फतवा देनेवाले अनवर सादत (महासचिव, मुस्लिम इंटीग्रेशन कौंसिल) ने २४ मार्च के मोर्चे का आयोजन किया था। उन्होंने ही 'इंकलाब' सहित कई उर्दू अखबारों में, जाने-माने मुस्लिम नेताओं के नाम सहित २४ फरवरी को प्रस्तावित मोर्चे का इश्तहार छपवाया था। एक सूचना के अनुसार

साक्षात्कार/**हाजी मस्तान**

मैं जानता हूं कि पुलिस क्या चीज होती है

अपने कैरियर और कारगुजारियों की बदौलत अखबारी सुर्खियों में रहे हाजी मस्तान के बारे में यह चर्चा फैली हुई है कि वे हिंसा और दंगा-फसाद के रास्ते अपने आपको मुस्लिम नेता बनाने में लगे हुए हैं। गत फरवरी में बंबई में १३ लोगों की जान लेनेवाले दंगे को भी 'मस्तान की ही देन' कहा जा रहा है। इस संदर्भ में प्रस्तुत हैं, 'माया' से मस्तान की बातचीत के मुख्य अंश :

माया: *आपको गिरफ्तार करते समय पुलिस ने आप पर क्या आरोप लगाये थे?*

मस्तान: पता नहीं। २३ फरवरी को मैं हैदराबाद से बंबई आया। रात में पुलिस पहुंची और बोली कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी का कोई भी कारण नहीं बतलाया गया।

माया: *पर आप इतने दिनों से राजनीति में हैं, आप विरोध प्रकट कर सकते थे, वारंट मांग सकते थे?*

मस्तान: पर मैं यह भी जानता हूं कि पुलिस क्या चीज होती है। विरोध करने पर वह कोई भी कदम उठा सकती है। उसने रात भर मुझे नजरबंद रखा, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो उन्होंने मुझे ५ बजे तक छोड़ देने का आदेश दिया। पुलिस ने रिहा करने के बजाय मुझे मझगांव कोर्ट में पेश किया और बंबई छोड़ देने का हुक्म दे दिया।

माया: *उसके बाद आप कहां गये?*

मस्तान: ठाणे गया, वहां से पूना चला गया। लेकिन वहां भी यहां जैसा ही किस्सा (निकाले का) दुहराया गया और देवलाली भेज दिया गया। फिर वापस पूना आया कि वहां से हवाई जहाज से दिल्ली चला जाऊं क्योंकि दिल्ली में अदालत में एक मुकदमा विचाराधीन था। लेकिन जब वहां भी पाबंदी लगा दी गयी तो मैं वहां से फिर पंजिम चला गया। वहां से कोयंबतूर, फिर कोडाईकनाल जाकर रहा। अभी-अभी यहां बंबई आया हूं।

माया: *पुलिस का तो आरोप है कि आपने ही २४ फरवरी वाला दंगा भड़काया था?*

मस्तान: पुलिस तो कुछ भी कह देती है। २३ को मैं हैदराबाद से बंबई आया, उसी दिन रात में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन बंबई से चले जाने के लिए कह दिया गया। तब से मैं लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। ऐसे में मैं भला दंगा कैसे भड़का सकता था? मेरे और दलित महासंघ के विरुद्ध एक भी ऐसा आरोप नहीं है और न ही मेरा इसमें विश्वास है।

माया: *तो फिर दंगा कैसे भड़का?*

मस्तान: पुलिस ने सब कुछ किया-कराया था। हमारा उस मोर्चे से (अनवर सादत के) कोई संबंध नहीं था।

माया: *१८ मार्च के मोर्चे (जियाउद्दीन बुखारी) और २० मार्च के आपके मोर्चे का उद्देश्य एक ही था, फिर अलग-अलग क्यों निकाले गये ये मोर्चे?*

मस्तान: १८ मार्च का मोर्चा कांग्रेस ने निकाला था। शरद पवार की सरकार ने हमारे मोर्चे को तोड़ने के लिए यह मोर्चा निकाला था। वे नहीं चाहते थे कि हमारा मोर्चा सफल हो, इसलिए उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा लिया। जो लोग मोर्चे में शामिल होने के लिए आ रहे थे उन्हें मलाड, मुलुंड, चेंबूर तथा दूसरी जगहों पर पुलिस ने रोक दिया।

माया: *आप सलमान रुश्दी की तो आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हिंदू देवी-देवताओं के बारे में बाबा साहब अंबेडकर की लिखी पुस्तक एवं रचनाओं का विरोध क्यों नहीं किया?*

मस्तान: बाबा साहब ने जो कुछ लिखा था उसे रामायण में लिखी बातों के आधार पर लिखा था। रुश्दी या कोई शख्स कुरान में लिखी बातों को आधार मानकर लिखता तो हम भी विरोध नहीं करते।

माया: *आपका 'रामायण' तथा 'महाभारत' सीरियल के बारे में क्या खयाल है?*

मस्तान: बहुत अच्छा सीरियल बनाया है उन्होंने। समय मिलने पर इन दोनों सीरियलों को देखता हूं।

—बंबई ब्यूरो

उन्होंने हाजी मस्तान से मिलकर उनका समर्थन भी हासिल किया था। यूं अब मस्तान इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन यह भी कहते हैं, "जहां मुसलमानों को हिफाजत की जरूरत है, वहां मेरा जाना जरूरी है। फिर मुरादाबाद, संभल तथा कानपुर के स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनावों में मेरी पार्टी के लोग खड़े हैं, इसलिए जरूरी है कि मैं उनका चुनाव प्रचार कर उन्हें जिताऊं। हमारी एकजुटता तथा ताकत से सरकार या तो खफा है या मन में डरी हुई है। इसीलिए वह रोज हम पर नयी-नयी बंदिशें लगाती है।"

उर्दू दैनिक 'इंकलाब' में मोर्चे के बारे में छपे विज्ञापनों ने लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। बहुत से मुस्लिम नेताओं की समझ में यह नहीं आ पाया कि अनवर सादत नामक यह नया 'सितारा' कहां से चमक गया और हाजी मस्तान के साथ ही कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का साथ-समर्थन उसने कैसे पा लिया, क्योंकि मोर्चे का समर्थन करनेवाले नेताओं की लंबी सूचियां २० से २२ फरवरी तक के अखबारों में लगातार छपती रहीं। इन विज्ञापनों के मद में भारी रकम खर्च की गयी।

मोर्चे का समर्थन करनेवालों में 'अखबारे आलम' के संपादक खलील जाहेद का नाम भी छपा था। जाहेद खुद सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लड़ाई में आगे रहे हैं। २२ फरवरी को उनका नाम देखकर उनके समर्थकों ने इस बाबत उनसे पूछताछ की, तब पता लगा कि इस बारे में न तो उनसे मशविरा किया गया था, न ही मंजूरी ली गयी थी। आग्रीपाड़ा के 'अल्लाह हो अकबर तंजीम' संगठन तथा उसके प्रमुख अलाउद्दीन सिद्दीकी ने मोर्चे में शामिल होने का बयान दिया। कुछ लोगों का शक है कि इस संगठन को हाजी मस्तान की आर्थिक मदद प्राप्त है, लेकिन वे इससे भी इनकार करते हैं।

हाजी मस्तान ने भले ही इस मोर्चे को खुला समर्थन नहीं दिया या दिया हो, लेकिन बंबई क्षेत्रीय कांग्रेस के महासचिव खान शहवाज खां के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अपील जारी कर कहा कि हिंद की हुकूमत ने रुश्दी की किताब पर सबसे पहले पाबंदी लगा दी। इसलिए जुलूस की जरूरत नहीं है। शहवाज खां ने 'माया' से कहा, "जो लोग मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि 'कुरान पाक' ने हर मजहब का ध्यान रखने को कहा है, दूसरे यह कि हिंद में ईरानी कानून नहीं चल सकते।"

खान शहवाज को तब यह अंदाज नहीं था कि यह मामला इतना अधिक भड़क जाएगा। किंतु महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री विलास सावंत ने साफ शब्दों में पुलिस कार्रवाई को सही और जरूरी बताया। उनका कहना था कि पुलिस को खबर लगी थी कि मस्तान की मौजूदगी से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए एहतियातन उन्हें बंबई आने से रोका गया। इसके साथ ही जनता दल के नेता शहाबुद्दीन तथा जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी पर पुलिस ने दो महीनों के लिए बंबई में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। विलास सावंत ने इस आरोप को भी गलत बताया कि सरकार ने परेशान करने के इरादे से हाजी मस्तान के खिलाफ कोई मुकदमा चला रखा है।

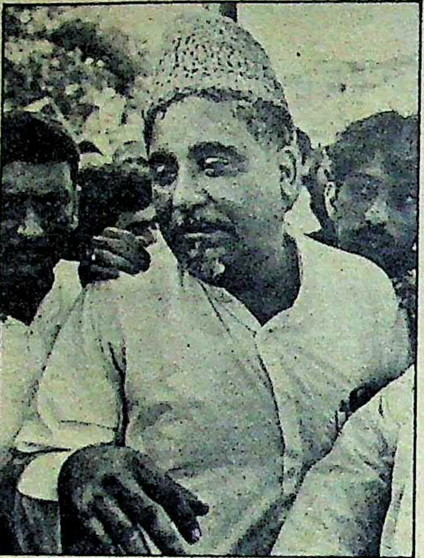

मस्तान के प्रतिद्वंद्वी : जियाउद्दीन बुखारी

इस तरह दंगों के वक्त मोर्चे के नेतृत्व का जिम्मा अनवर सादत पर आया। एक बड़े नेता ने बताया कि जब लोगों की जानें जा रही थीं, तब सादत पुलिस थाने में पनाह लिये हुए थे। बंबई के मुस्लिम नेता यूं भी उनकी खरी आलोचना करते हैं तथा उन पर झोपड़ी यूनियन बनाकर ज़बरन चंदा वसूली आदि के आरोप लगाते हैं, लेकिन अनवर सादत इन आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने बंबई के एक अखबार को दिये गये साक्षात्कार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि की खिंचाई करते हुए आरोप लगाया था कि मुस्लिम नेता 'बिक' गये हैं और मुस्लिम लीग एक तरह से कांग्रेस का ही हिस्सा बन गयी है। इस कांग्रेसी शासन में मुसलमान दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं। अनवर सादत के इस आरोप की चर्चा उठने पर हाजी मस्तान का कहना था, "इस तरह की घटनाएं (२४ फरवरी की फायरिंग, २० मार्च के उनके मोर्चे के बारे में पुलिस की शर्तें आदि) इस बात का प्रमाण हो सकती हैं।"

अनवर सादत इसलिए भी हाजी मस्तान की तर्ज पर, कांग्रेस, शरद पवार, पुलिस प्रशासन की आलोचना करते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा दूसरे नेताओं ने उनके मोर्चे का विरोध किया था। दूसरी तरफ हाजी मस्तान की नाराजगी बंबई, पुणे, सोलापुर, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में उनके प्रवेश पर पाबंदी के कारण भी है। इसके विरोध में उनके वकील अनीस सुहरावर्दी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मस्तान के मौलिक अधिकारो के संरक्षण की मांग की। याचिका में बताया गया कि उत्तर प्रदेश जाने के लिए अनुमति मांगी गयी, परंतु २३ फरवरी को सुनवाई मुल्तवी हो गयी। उसी रोज मस्तान को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहां छोड़, तो फिर पुणे में गिरफ्तार किया गया। फिर बंबई-पुणे से उन्हें शहरबदर किया गया। यहां तक कि वे अदालती सुनवाई के लिए २८ फरवरी को दिल्ली पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके दिल्ली-प्रवेश पर भी रोक लगा दी गयी।

बढ़ावा किसका ?: आम तौर पर लोग यह मानते हैं कि रुश्दी ने कई ऐसे मुसलमान नेताओं को फिर विश्वसनीयता या चमक दी है जिनकी सूची सैयद शहाबुद्दीन से शुरू होती है। हाजी मस्तान भी इसी दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। इसके पहले बंबई में उनका रुतबा तब बढ़ा था, जब उन्होंने शाहबानो प्रकरण को लेकर जुलूस निकाला था। ऐसा तो कोई नेता ही करेगा, किंतु गूढ़ रहस्य यही है कि उन्हें नेता कौन बना रहा है ? मध्य बंबई की मुस्लिम बहुल आबादी में सक्रिय एक सामाजिक कार्यकर्ता का मत है कि शिवसेना के बढ़ते प्रभाव पर रोक के लिए कुछ कांग्रेसी मस्तान को आगे लाना चाहते हैं। वैसे भी महाराष्ट्र के दोनों मुसलमान मंत्रियों (इसाक जामखानावाला और जावेद खान) का अपनी बिरादरी में कोई असर नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेता शहवाज खां का सवाल है, "मस्तान को ही मुस्लिम बिरादरी में कितना सम्मान और समर्थन प्राप्त है ?"

शिवसेना की मस्तान से दोस्ती है। बंबई महानगर पालिका में बहुमत न होने के बावजूद तीन साल से शिवसेना का महापौर जीतकर आ रहा है। दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक महासंघ यानी हाजी मस्तान की पार्टी के तीनों नगरसेवक शिवसेना को वोट देतेरहे हैं। एक महासंघ नगरसेवक की मौत के बाद उपचुनाव में कांग्रेस और महासंघ के टकराव में शिवसेना ने परदे के पीछे से महासंघ की मदद की।

वैसे आजकल यह माना जाता है कि पाताल लोक की अंधेरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए शिवसेना, दाऊद और मस्तान दोनों का खात्मा चाहेगी। अब तक शिवसेना सिर्फ दाऊद गिरोह के खिलाफ बोलती थी। ऐसे में कांग्रेस और मस्तान क्या करेंगे ?

हेमवती नंदन बहुगुणा के निधन के बाद अल्पसंख्यक वर्ग के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का सवाल उठ खड़ा हुआ है। आरिफ मोहम्मद का प्रभाव नयी पीढ़ी की मुस्लिम जमात पर तो है, लेकिन सवाल रुढ़िवादी पीढ़ी का है। ऐसे में इस खालीपन को भरने के लिए कांग्रेसी नेता हाजी मस्तान को आगे कर आरिफ मोहम्मद और उनके जनता दल को टक्कर देने की कोशिश कर सकते हैं। फिर वे कहते भी हैं, "सिख भी हमारे साथ है।" यूं हाजी मस्तान मई में दिल्ली में एक विशाल मोर्चा आयोजित करने की घोषणा कर चुके हैं। तब शायद उनकी असली ताकत का पता लग जाए जो २० मार्च को पुलिस नाकेबंदी के कारण नहीं लग पाया था।

—बंबई ब्यूरो

"सितारे हैं अनेक, नाम सिर्फ एक-खेतान"

हेमा मालिनी, राज बब्बर, पद्मिनी, राधिका, देविका... मैगनेट, बैरॉन, टाइकून, डाइनेस्टी, मिनि, चिकि, मिकि, विकि, रूपा, सोना...हमारे सितारों की सूची काफी लम्बी है। कार्यकुशलता और सुन्दरता में सभी एक से बढ़कर एक!

हर खेतान पंखा, हमारे अपने आधुनिकतम कारखानों में निर्मित है। यानी १००% खेतान! तभी तो खेतान की उत्कृष्टता अर्थात बेजोड़ क्वालिटी भरोसेमंद है!

घर हो या दफ्तर, दुकान हो या गोदाम, बाथरूम या रसोईघर, सिनेमा हॉल या थियेटर, कारखाना अथवा फाउण्ड्री। १३५ से भी अधिक किस्मों के सीलिंग, टेबल, दीवाल, केबिन, पेडेस्टल, कूलर एग्जोस्ट, एयर सर्कुलेटर, एक्सियल फ्लो आदि पंखे विभिन्न मॉडलों, रंगों व साइजों में उपलब्ध हैं। सच तो यह है–चाहिये हवा जहाँ, खेतान है वहाँ!

चिकि
टाइकून
आयुष
हीरा सुपर डीलक्स
सोना पेडेस्टल
मिनि सुपर
बैरॉन
फ्रेशएयर

3595 A

खेतान - सिर्फ नाम ही काफी है

रंग बिरंगी सूती कमीजों की बाढ़

दुनिया भर के फैशन-निर्माता तरह-तरह के कपड़ों, रंगों और डिजाइनों की कमीजें बाजारों में सजाये बैठे हैं। पर अधिकांश खरीदार मुलायम कालरवाली ढीली-ढाली सूती कमीजें ही क्यों पसंद करते हैं?

रंग और उमंग: रंगीन कमीजें चुनता एक युवक

पिछले कुछ सालों में मध्यवर्गीय कमीज की पसंद में भारी तब्दीली हुई है। नतीजतन सीधी-सादी कमीज के स्थान पर भड़कीली एवं लुभावनी कमीजों का जमाना आ पड़ा है। पहले कालर की पट्टी पर 'लेबल' लगाये जाते थे जिन पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी। किंतु आज इन 'लेबलों' को ऐसी जगह चस्पा किया जाता है, ताकि नजर पड़ते ही देखनेवाला जान ले कि कमीज फैशन की दुनिया के किस कोने से डिब्बों में बंद होकर काउंटरों तक पहुंची और फिर शरीर तक पहुंची।

पसंद अपनी-अपनी: इस साल सूरज के गरमाने से पहले ही गरमी की पसंद लगभग तय हो चुकी है। समूचे उत्तर भारत में तापमान चढ़ रहा है और सब दुकानदार तेजी से अपनी दुकानें सजाने में जुटे हैं। जो नया माल आ रहा है, वह 'लकोस्ट' का सीधा-सादा नहीं, बल्कि भड़कीले लेबलवाला और कढ़ाईदार है।

वर्गगत बड़प्पन के अतिरिक्त परंपरागत, आधुनिक, अधिकारी और कालेज से अभी-अभी निकले युवक की पसंद के बीच होड़-सी मची है। मजे की बात तो यह है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपनी कमीजों की पसंद के आधार पर अपने से नीचा मानता है। जाहिर है, संजीदा उम्र की पसंद जहां देखने में शांत, सौम्य 'ब्रितानी' थी, तो कमउम्रों की पसंद बिलकुल चंचल चमकदार 'अमरीकी'। इस बार गर्मियों में ऐसा लगता है कि परिधान की पसंद का यह अंतर बहुत कम हो जायेगा। इस साल पीढ़ियों से चले आ रहे सूती धागे की जीत होगी और वही 'लोक रुचि का वस्त्र' साबित होगा। सूती धागे का यह उद्भव परंपरागत और अपरंपरागत कपड़ों को एक दूसरे के काफी करीब ला देगा। यह भविष्यवाणी है दिल्ली स्थित फैशन निर्माता रवि बजाज का जिनका कहना है, "सौ फीसदी सूती कपड़े का फिर पदार्पण हो रहा है। अधिकाधिक व्यक्ति अब सूती वस्त्र अपना रहे हैं। इस गरमी में तो सभी आयु तथा वर्ग के लोग सूती कपड़ों के बड़े-बड़े आर्डर दे रहे हैं।"

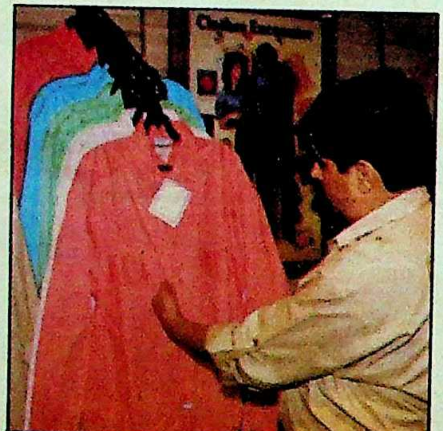

चाहत और चुनाव: ढीली-ढाली कमीज देखता एक ग्राहक

इतने पहले से सूती कपड़ों के प्रति लोगों की चाह देखकर यह कहना गलत न होगा कि इस बार गर्मियों में सूती वस्त्रों का प्रचलन आम होगा। इसका मतलब यह नहीं कि फैशन की दिशा निर्धारित करनेवाले परंपरा की ओर लौट रहे हैं। फैशन की दिशा तो आज भी चमक-दमकवाली, रंगभरी और धड़कन पैदा करनेवाली ही है। युग जिस गति से भाग रहा है, फैशन की गति उससे भी तेज है। पर ऐसे उत्साही और उत्सुक युवक हमेशा रहते हैं, जो फैशन की दिशा निर्धारित करते हैं तथा उसके कदम-से-कदम मिलाकर चलते हैं। कल की ही बात है कि चुस्त कमीजों का फैशन था। पर अब ढीली-ढाली कंधे से नीचे लटकती, चौड़ी आस्तीन, मुलायम कालर और बड़ी जेबवाली 'बैगी' कमीजों का जमाना है। अब की गर्मियों में ये ढीली-ढाली 'बैगी' कमीजें ही फैशन का रुख निर्धारित करेंगी।

बैगी कमीजों का दौर: बैगी कमीज पहन कर कैसा महसूस होता है? "शानदार, यार! इतनी आरामदेह!" यह मत है कालेज से निकले युवा नितिन खन्ना का। यह पूछे जाने पर कि कमीज का चयन आराम की दृष्टि से किया जाता है या स्टाइल की दृष्टि से जिसका फैशन बाजार में अभी-अभी पदार्पण हुआ है? वे बोले, "देखिये, फैशन भी आराम को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मैं ऐसा ही मानता हूं। बैगी कमीजें आपके शरीर को सांस लेने और हिलने-डुलने का मौका देती हैं।" जबकि अधेड़ वय के एक अधिकारी मानते हैं, "बैगी कमीजें दफ्तर लायक नहीं।" हालांकि २८ वर्षीय हाट अधिकारी विवेक गुप्त इसे अस्वीकार करते हैं। जान पड़ता है बैगी पहन कर दफ्तर जाने में वे सुख का अनुभव करते हैं। पर एक फुटकर विक्रेता ने कुछ अनमने मन से कहा, "नौजवानों को आराम सस्ते में नहीं मिलता।"

बैगी कमीजों पर लिखी कीमत से इसकी पुष्टि होती है। 'एफ्यूज', 'न्यूमैन', 'बाटा' (नार्थ स्टार शृंखला में) बेनेटोंन्स और इटरनेशनल न्यूज की कीमत किस्म के अनुसार १२५ रुपए से ४०० रुपए तक है। यदि यह बारीक कपड़े की ढीली-ढाली कमीज है, तो इसका मूल्य बड़े आराम से १२५ रुपए तक हो सकता है। लेकिन इस फैशनवाली मोटे कपड़े

की और टिकाऊ कमीज २०० रुपए से कम में नहीं मिलेगी। यह महंगी इसलिए है कि पतले कपड़ेवाली टिकाऊ नहीं होती।

दूसरी ओर फुटपाथ पर बैठकर कमीजें बेचनेवालों से कमीजें ५० रुपए की दर से खरीदी जा सकती हैं। फुटपाथवाले इन्हें नीले, हरे, नारंगी, लाल, पीले, खाकी आदि रंगों में सजा कर टांगते हैं। इनमें से कुछ रंगों को पहले जनाना रंग माना जाता था। किंतु इस बार गर्मियों में किसी युवक को भड़कीले लाल रंग की कमीज पहने देखकर शायद अनुदारवादियों की भौहें न तनें। इस बार गर्मियों में नवयुवक ज्यादा रंगीन नजर आयेंगे। पर सफेद, गहरे रंग के चेक और चौड़ी धारीवाली कमीजें भी पूरे जोर पर होंगी। नवयुवकों की कमीजों के सीने पर जिप और बड़ी-चौड़ी थैलियों पर पीतल के चमकदार बटन भी शोभा देंगे।

पांच वस्त्र निर्माताओं में से तीन-मुरजानी, इण्टरनेशनल न्यूज और बेनेटोन्स (शेष दो हैं इंटरशाप और न्यूमैन) रंगीन, धारीदार और नये भड़कीले रंगवाली कमीजों के साथ संभावित ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में आ गये हैं। इंटरनेशनल न्यूज कोई बड़ी न्यूज नहीं बना सकी, क्योंकि उसकी कमीजें सस्ते कपड़े की हैं और बहुत महंगी भी हैं। दूसरी ओर इटली की बेनेटोन्स बाजार में आंधी की तरह छा रही है। नयी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में बेनेटोन्स के शोरूम की प्रबंधक हनी बेदी का कहना है कि ग्राहकों ने इनका गजब का स्वागत किया है। पर एफ्यूज की इंटरशाप और न्यूमैन की ढीली-ढाली 'बैगी' कमीजें बढ़िया किस्म के कारण आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। ये सूती बैगी कमीजें धड़कन पैदा करनेवाले रंगों में ६० रुपए से लेकर २०० रुपए तक मिल जाती हैं।

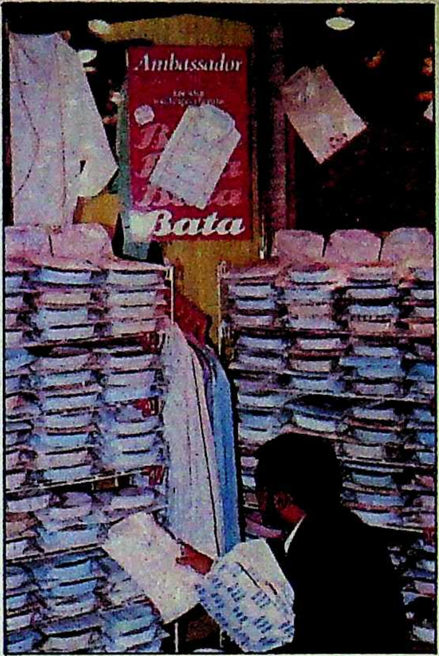

लोकरुचि का तकाजा : भरे रेकों में से एक कमीज पसंद करता एक युवक

इस वर्ष नवयुवकों की पसंदवाले लेबल बहुत सीमित हैं (सिर्फ पांच)। हालांकि परंपरागत शैली की कमीजों में पसंद करने के लिए बहुत हैं—स्टेंसिल, राड लावर, स्टैग, नाइन एएम, स्नोह्वाइट, जोडियेक और बाटा की नयी 'एम्बेसडर'। ये निर्माता डिजाइन में ज्यादा फेरबदल किये बिना सीमित रंगों में सौम्य पैटर्न की कमीजें तैयार करते हैं। जो फैशन के साथ नहीं चलते उनको तो आज भी वही कमीजें पसंद हैं, जो क्लार्क कैबल ३० वर्ष पूर्व पहनते थे। रायल्स रायस की तरह उनकी श्रेणी ही अलग है। पुरुषों के फैशन में आये रंगों के तूफानी बदलाव से अप्रभावित परंपरावादी वही अपने सीधे-सादे रंगों को ही पसंद करते हैं। यदाकदा थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। पर यह सतही होती है। धारी की जगह चेक आ जायेगी और काले-भूरे की जगह नीला रंग ले लेगा। सो जहां तक पारंपरिक दृष्टि का ताल्लुक है उसके लिए तो १९८९ की गरमी, १९८८ की गर्मियों से भिन्न न होगी।

रंग-बिरंगी कमीजों की भरमार : चौड़ी और पतली धारीदार कमजों से तो रेक भरने लगे हैं। पेस्टेल रंग वाली, खासकर नीले, सफेद, मटमैले, हलके भूरे, हलके हरे और आड़ू जैसे रंगवाली कमीजें तो पहले की ही तरह लोकप्रिय रहेंगी। कालर अब मुलायम हो गये हैं, जिससे गले के चारों ओर वे आसानी से जम जाते हैं। अब चौड़े और कड़े कालरवाली कमीजें देवानंद जैसे लोगों को छोड़कर शायद और कोई नहीं पसंद करता।

किंतु परंपरागत शैली के साथ चलना सस्ता है। ऐसी कमीजों की कीमत ८५ रुपए से २४ रुपए (पूरी बाजू या आधी बाजू की) तक है। टेरीकाट की कमीजें ६० रुपए से ३०० रुपए तक में आ जाती हैं। पर इस बार सूती कमीजें अधिक पसंद की जायेंगी।

अनुमान है कि पारा जैसे-जैसे चढ़ेगा सामान्य और औपचारिक पहनावे का फर्क कम होता जायेगा। इस बार गर्मियों में आधी बाजू और पूरी बाजू की ऐसी कमीजें उपलब्ध होंगी जो किसी भी मौके पर पहनी जा सकेंगी। यदि आप अपने भुजदण्ड प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो नौ प्रकार की आधी बाजू की कमीजें बाजार में उपलब्ध होंगी। आपकी जेब में बस पैसा होना चाहिए। यदि आपकी जेब में एक हजार रुपए हैं, तो आप पांच छह सूती कमीजों के डिब्बे सीने से चिपकाये हुए लौट सकते हैं और गरमी के बीच ठंडक का अहसास कर सकते हैं।

—अरुंधती गुप्त

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

फ्रांसीसी झलक का प्रवेश

भारतीय परिधान के क्षेत्र में अब फ्रांसीसी झलक प्रवेश करने की तैयारी में है। हाल में ही फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर मोशिये कार्डिन ने दिल्ली से २५ किलोमीटर दूर सूरजकुंड के राजहंस होटल में अपने भड़कीले वस्त्रों के नमूने पेश किये। पर देखनेवालों में इन डिजाइनों से कोई फुरफुरी नहीं मची। पहली बात तो यही रही कि पुरुष परिधानों में कोई खास बात नहीं नजर आयी। मंच पर माडेल प्लेटवाली पैंट और बैगी कमीज पहने प्रविष्ट हुए। वे ऐसे लगते थे मानो पुरुषों के आधुनिक परिधानों की किसी दुकान से निकलकर आ रहे हों। प्रदर्शित कमीजों में—शिफोन, रेशम, सूती, ऊनी के अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं थी।

कार्डिन ने पुरुषों की कमीज के लिए चटख रंगों—मैजेंटा, पीला, गुलाबी मरकत हरित—का प्रयोग किया। लड़के-लड़कियों द्वारा समान रूप से पहनी जानेवाली कमीजों के लिए भी यही रंग चुने गये। पर खादी की इन कमीजों की कीमत १८५ रुपए प्रति कमीज होने के कारण कार्डिन के ठप्पे के बावजूद ये बहुत कम बिकीं। यानी कार्डिन द्वारा भारतीय हथकरघा का प्रयोग (सब वस्त्र हथकरघे पर उत्पादित कपड़े से निर्मित थे) विफल रहा।

दूसरी ओर स्वदेशी वस्त्र निर्माता पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख रवि बजाज हैं। दिल्ली में उनकी प्रर्दशनी कक्ष सबके, खासकर पुरुषों के, आकर्षण का केंद्र है। इस गरमी में वे चीनी क्रेप, लिनेन, सूती और शीट बकर कमीजों का परीक्षण करनेवाले हैं। उनका कहना है, "कोट के साथ कमीज जंचती है। पुरुष यदि मोटे सफारी सूट पहन सकते हैं, तो सूती कोट क्यों नहीं पहन सकते ?"

बजाज कहते हैं कि पुरुषों को शाम को वास्केट पहनना चाहिए। यदि चीनी या प्लेटदार कालरवाली कमीज पर वास्केट पहनी जाये, तो जंचती है। वे चीती क्रेप और रेशमी कपड़े से वास्केट बनाते हैं। उनका कहना है कि बैगी कमीज पर वास्केट या कोट पहन कर व्यक्ति खूब जंचता है।

बजाज की डिजाइन पर तैयार की गयी चटकीले रंगों में प्लेटदार कालर, चीनी कालर, बटन अप कालर, बड़ी-बड़ी जेबों, छोटी जेबों, सामने लगे अनगिनत बटनोंवाली कमीजें इस बार गरमी में उपलब्ध होंगी। परंपरागत शैली की कमीज पसंद करनेवालों को पीच, पेस्टेल, लेमन और अक्वा रंग की खादी की और नवयुवकों के लिए चटकीले हरे, गहरे नीले, नारंगी, मार्लब्रो लाल और पीले रंग की कमीजें उपलब्ध होंगी। कमीजों की यह श्रेणी ग्रीष्म ऋतु के धुपहले प्रतिबिंब के अनुरूप होगी।

—अ०गु०

टीना मुनीम का शाप

संजय दत्त को इस बात का कतई अहसास नहीं था कि किसी का दिल तोड़ने से क्या होता है, लेकिन जब से उन्होंने टीना के साथ बेवफाई की, तब से वे विपत्तियों के भंवरजाल में फंसते जा रहे हैं।कुछ तो वे अपनी मां की मौत से लगे धक्के को बरदाश्त नहीं कर पाये और कुछ रेखा के चलते बदनाम हो गये। एक समय तो ऐसा आ गया कि वे मारपीट और हवाई फायरिंग जैसे कांडों में फंस गये जिसके चलते उनके सभी निर्माताओं ने कुट्टी कर ली, हीरोइनें उनसे कतराने लगीं। विवाह तो कर लिया, पर पता चला कि अभी भी वे असाध्य रोग की गिरफ्त में हैं। तो अमरीका जाकर लंबा आपरेशन करवाया और सपरिवार लंदन होते हुए बंबई आये। अब जब फिल्म 'हथियार' (निर्देशक: जेपी दत्ता) में उनके सशक्त अभिनय की तारीफें होने लगीं तथा फिल्म निर्माता उन्हें साइन करने लगे तो फिर वे एक नयी मुसीबत में फंस गये। यह आफत है उनकी पत्नी ऋचा दत्त (शर्मा) को असाध्य ब्रेन ट्यूमर की शिकायत, जिसका पता चलते ही वे १८ मार्च को ऋचा को लेकर इलाज के लिए अमरीका चले गये—सारी शूटिंगें रद्द कर।

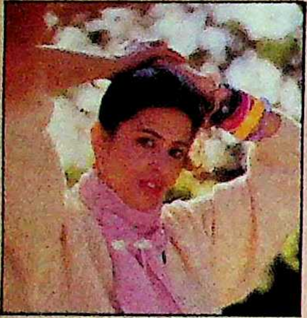

ऋचा शर्मा छाया: तैयब बादशाह

कुछ फिल्मी खबरचियों का तो कहना है कि राजेश खन्ना से कन्नी काटकर अमरीका में ही रह रहीं टीना मुनीम शायद अब खुश होती होंगी, क्योंकि जब संजय ने उनसे बेवफाई कर रति अग्निहोत्री से 'दोस्ती' कर ली थी, तो टीना ने सबके सामने शाप दिया था—''ठीक है, तुम सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाओगे।''

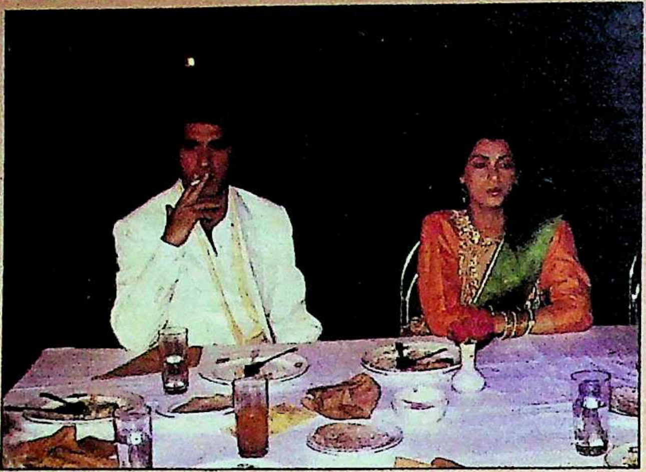

डिंपल कपाड़िया और राज बब्बर 'कर्मयोद्धा' में छाया: विमोर

राज बब्बर की चुनावी मुहिम

अपने ऊपर विपक्षियों द्वारा थोपे गये इल्जामों का जवाब देने के लिए अमिताभ बच्चन द्वारा बनवायी गयी 'सच' अभी डिब्बे में ही पड़ी थी कि उसके विरुद्ध राज बब्बर ने दयाल निहलानी को बतौर डायरेक्टर लेकर 'कर्मयोद्धा' की शुरुआत कर दी। दयाल निहलानी ने 'अंधा युद्ध' में राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा युवकों को अपने 'हितों' के लिए तो इस्तेमाल किये जाने की मानसिकता को बड़ी बेबाकी से बेनकाब किया था, लेकिन राज बब्बर को महसूस हुआ कि भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए इतना 'सच' पर्याप्त नहीं है। जो बात वीपी सिंह गली-गली घूमकर कहने की कोशिश कर रहे थे, उसे सिनेमाई अंदाज में राज बब्बर ने कहने की जंग छेड़ दी है। वे पहले 'कर्म योद्धा' में रेखा को लेना चाहते थे, जिनके साथ उनके 'गुप्त विवाह' की खबर उनके 'विरोधियों' ने उड़ा दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके एक 'विरोधी स्टार' ने रेखा को उनके विरुद्ध इस्तेमाल किया था, तब उन्होंने अपनी सूची से रेखा का नाम काटकर डिंपल कपाड़िया का नाम दर्ज कर दिया, जिन्हें रेखा अपना 'अव्वल नंबर' का शत्रु मानती हैं। लेकिन जाहिरा तौर पर राज बब्बर इसे नकारते हैं और 'कर्मयोद्धा' को एक आम फिल्म भर मानते हैं। इसके विपरीत एक जाने-माने फिल्मकार का मानना है कि इन फिल्मों के जरिये अमिताभ ('सच'), राज बब्बर ('कर्मयोद्धा') तथा एनटी रामाराव ('विश्वामित्र') आगामी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं।

विजया शांति का रौद्र रूप

एक बंबइया फिल्म निर्माता 'ईश्वर' देखते ही भागकर मद्रास पहुंचा और विजया शांति को 'सुपर हिट ऐक्टिंग' के लिए बधाई देते हुए बोला, ''बस जी, आप मिल गयीं और हमारी इंडस्ट्री श्रीदेवी के नखरों से बच गयी। अब आप ही उनकी जगह लेंगी।'' फिर एक सादा कागज उनकी तरफ बढ़ाया, ''आप अपनी जो भी 'प्राइस' चाहें, इस पर लिख दें। श्रीदेवी से भी ज्यादा मैं दूंगा।'' यह सुनते ही विजया शांति ने अचानक रौद्र रूप धारण कर कागज को तोड़-मरोड़कर उस निर्माता के चेहरे पर उछाल दिया—''प्लीज गेट आउट। मैं न तो नंबर वन बनना चाहती हूं, न ही वैजयंती माला, और न ही श्रीदेवी, रेखा या जयाप्रदा! मैं विजया शांति हूं और यही बनी रहना चाहती हूं। न मैं ग्लैमरस सीन करूंगी न बिकनी या स्वीमिंग कास्ट्यूम पहनूंगी और न ही चुंबन दृश्य दूंगी। इस तरह के आफर सुनते-सुनते मेरे कान पक गये हैं।'' उनके इस रौद्र रूप का बेचारे उस निर्माता पर क्या असर पड़ा पता नहीं, लेकिन खुद को विजया शांति का 'गाड फ्रेंड' मान कर उसकी सिफारिश करनेवाले अनिल कपूर अभी भी दावा करते हैं—''नर्गिस और वैजयंती माला जैसी अभिनेत्रियों के बाद सिर्फ विजया शांति का ही नाम लिया जा सकता है।''

विजया शांति छाया: तैयब बादशाह

सनी देवल और माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित की भविष्यवाणी

फिल्म 'यतीम' ने फिल्म मार्केट में यतीम हो रहे सनी देवल की ऐसी भाग्य रेखा बदली कि एन चंद्रा ने उन्हें अपनी फिल्मों में फिर से लेना शुरू कर दिया है। यही नहीं, जो माधुरी दीक्षित अनिल कपूर के कारण उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती थी, उसने सनी के साथ कई फिल्में साइन कर लीं। सुनने में तो आता है कि अनिल कपूर और सनी देवल के बीच डिंपल के कारण जो दीवार खड़ी हो गयी थी, वह भी खतम हो गयी है।

शायद इसीलिए सनी 'यतीम' से ज्यादा चर्चा 'त्रिदेव' की करते हैं जिसमें माधुरी उनकी नायिका है और माधुरी का दावा है कि इसके बाद सनी भी 'तेजाबी' अनिल कपूर जैसा सितारा बन जायेगा!

—अखबारी लाल

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस,
३-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका

माया

वर्ष ६०, अंक १०
३१ मई, १९८९

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

17/5/89

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमिन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५ जयपुर कार्यालय: ए-२० शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर-४ फोन: ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silcher, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

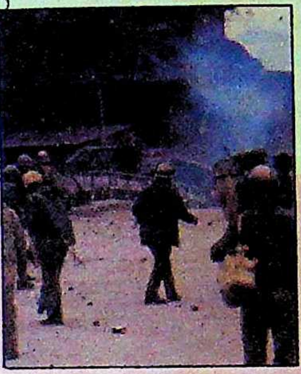

३०

आवरण कथा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वे हिंदुस्तान की लड़ाई कश्मीर की गलियों में लड़ रहे हैं। कश्मीर घाटी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फारूक का यह कथन निराधार नहीं लगता। 'माया' की सूचना के अनुसार पाकिस्तान का १३ जुलाई, १९९० को कश्मीर में भयानक स्थिति उत्पन्न करने का षड्यंत्र था। यह षड्यंत्र क्या था और इसका भेद कैसे खुला? कश्मीर के रास्ते देश पर पाकिस्तान के अघोषित हमले का अंदरूनी जायजा

फारूक का साक्षात्कार
कश्मीर में पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों और कट्टरपंथी तत्वों से जूझ रहे फारूक अब्दुल्ला का विशेष साक्षात्कार
४०

माया विशेष
अरुण नेहरू से माया का दोटूक विशेष साक्षात्कार जिसमें उन्होंने राजीव गांधी व बूटा सिंह को कतई नहीं बख्शा।
४५

कर्नाटक
बोम्मई सरकार के गिरने के बाद पक्ष-विपक्ष की राजनीति में कैसी उठापटक मची हुई है?
१७

उत्तर प्रदेश
क्या नारायणदत्त तिवारी देश की राजनीति के निर्णायक प्रदेश को कांग्रेस-इ के पक्ष में मोड़ने में सफल हो सकेंगे?
५१

अर्जुन सिंह
अर्जुन सिंह ने २४ अप्रैल को भोपाल में जो सिंहगर्जना की, उसे मोतीलाल वोरा के खिलाफ जेहाद क्यों कहा जा रहा है?
२२

बिहार
बिहार की नौकरशाही का किसी जमाने में बड़ा नाम था, लेकिन आज वह रसातल में कैसे पहुंच गयी?
५६

दिल्ली दरबार: बूटा की करामात ८
फोटोफीचर १३
घटनाक्रम: रेल दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? २६
प्रसंगवश: पामेला का इस्तेमाल! ६२
विदेश: भ्रष्टाचार की ईमानदारी? ६४
राजस्थान: पर्यटन व्यवसाय की असलियत ६६
राजस्थान: कांग्रेस की चुनावी मुहिम ७४
मध्य प्रदेश: आखिर क्यों बंद हुई सरकारी लाटरी? ७६
मध्य प्रदेश: जनता दल का अंतर्कलह ७८
उत्तर प्रदेश: अंबेडकर विश्वविद्यालय:
हरिजनों के लिए चुनावी चुग्गा ७९
दूरदर्शन: 'डाक्टर साहब': एक आदर्श
डाक्टर की कहानी ८४
व्यक्तित्व: इमरान खान:
तलाश एक अदद बीवी की ८६
स्त्री: सुंदरता का उद्योग ८९
फिल्म: अशोक कुमार: आज भी है
अंदाजे बयां कुछ और ९०
बेढब ९५
परदे के पीछे ९६

पर्सनल

आत्मविश्वास.
मर्द... जो अपने दिल की सुनें, फ़ैसला दिमाग़ से करें और अपनी ज़िन्दगी को अपनी सोच के सांचे में ढालें.

विमल ऐसे मर्दों को देते हैं दाद और एक अतिरिक्त आत्मविश्वास. बेहतरीन शर्टिंग फैब्रिक.

जो नतीजा है के आला दर्जे का फ़ाइबर व यार्न की प्रोसेसिंग में ख़ास ध्यान और ख़ास नज़र का.

यह तभी हो सकता हे, जब एशिया का सबसे आधुनिक इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल प्लांट आपका अपना हो.

कपड़े की ईजाद करते हुए एक सटीक कल्पना करना कि यह सिलने के बाद कैसे खिलेगा और पहनने के बाद कैसे लगेगा... डिज़ाइनों का जैसे अंबार... क्योंकि २८०० से भी ज्यादा डिज़ाइन हर साल.

प्रीमियम शर्टिंग फ़ैब्रिक है उन मर्दों के लिए, जिनमें हो एक ख़ास बात... आत्मविश्वास.

आपकी ख़ास पसंद के लिए ख़ासुलख़ास लाए हैं विमल. तन पर सजे - मन की बात कहे.

पावर

प्रीमियम शर्टिंग्स

VIMAL®
A RELIANCE PRODUCT

Mudra:A:RIL.4690. Hin

माया
इंदिरा हत्याकाण्ड
व्यापक षड्यंत्र
या चुनावी हथकंडा

इंदिरा हत्याकांड : व्यापक षड्यंत्र या चुनावी हथकंडा ?

'माया' के ताजे अंक (१५ मई, १९८९) की आवरण कथा 'इंदिरा हत्याकांड : व्यापक षड्यंत्र या चुनावी हथकंडा ?' पढ़कर आंखें ही खुल गयीं। कांग्रेस-इ चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी के मौत का मसला पुन: उठायेगी, यह सोचकर बड़ी हैरत हुई। ऐसा भला कौन होगा जो यह न चाहेगा कि श्रीमती गांधी के हत्यारों को उजागर कर उन्हें सजा दी जाये, लेकिन पांच साल बाद यह सब क्यों किया जा रहा है ? विपक्ष का यह कहना कि यह सब धवन को बचाने की प्रक्रिया के तहत हो रहा है, सही जान पड़ता है। साथ ही इंदिराजी की हत्या में विदेशी हाथ होने की बात भी कुरसी बचाने और अगामी चुनावों में लोगों के जजबात भड़काकर वोट लेने की कांग्रेस-इ की पुरानी रणनीति ही लगती है। पंजाब पैकेज पेश करने से भी कांग्रेस-इ का यही मंशा सिद्ध होता है कि वह पंजाब-समस्या हल करने के लिए नहीं वरन वोटों को पाने की जुगाड़ में यह सब कर रही है।**—एंथोनी वीके, कोटेब, केरल**

ठक्कर रिपोर्ट : सरकार के गले में एक और फंदा

'माया' के ३० अप्रैल के अंक में ठक्कर रिपोर्ट पर आधारित विस्तृत सामग्री पढ़ने को मिली। ठक्कर आयोग की रिपोर्ट ने इंदिरा गांधी हत्याकांड को एक नये दृष्टिकोण से देखने को विवश कर दिया है। इसके चौंकानेवाले विस्फोटक रहस्योद्घाटनों ने जनमानस को उद्वेलित कर दिया है और वह वास्तविक हत्यारों का नाम जानने को बेहद उत्सुक है। इसके अंतर्गत धवन पर संदेह करने के पर्याप्त आधार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस हत्याकांड में उनकी अहम भूमिका रही है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने राष्ट्रहित के नाम पर रिपोर्ट को क्यों दबाया हुआ था। जब एक चौथाई रिपोर्ट के प्रकाशन होने के उपरांत यह आलम है, तो पूरी रिपोर्ट के बाद तो स्थिति और नाजुक हो जायेगी। इस रिपोर्ट के निष्पक्ष और पूर्वग्रहरहित अध्ययन के बाद असली षड्यंत्रकारियों का जब परदाफाश होगा, तो लोगों का शक, यकीन में बदल जायेगा। किंतु वर्तमान सरकार के गद्दीनशीन रहने तक ऐसा संभव नहीं है।**—सुरेंद्र साह, लोदी रोड, नयी दिल्ली।**

चंद्रशेखर बनाम वीपी सिंह

'माया' (३० अप्रैल' ८९) में विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत जनता दल में चंद्रशेखर और वीपी सिंह के शीतयुद्ध पर पेश जायजा पढ़ा। कई दलों तथा विभिन्न स्वभाव के नेताओं को मिलाकर एक दल के गठन से नेताओं के बीच थोड़ा-बहुत वैचारिक मतभेद या पद-लालसा का आना स्वाभाविक है। अत: जनतादल में हो रही खींचातानी को अस्वाभाविक करार नहीं दिया जा सकता। जहां तक विपक्षी एकता पर जनता के विश्वास की बात है, १९७७ में जनता पार्टी के सत्तासीन होने तथा चंद महीनों पश्चात कुरसी की लड़ाई में पार्टी के सत्ताच्युत तथा छिन्न-भिन्न होने के पूर्ण घटनाचक्र के बाद से जनता विपक्षी एकता पर विश्वास करने को कतई तैयार नहीं है, अत: विपक्ष द्वारा जनता को मन जीतना नितांत अनिवार्य है। **—श्रीमती मंजु शक्तावत, रघुनगर, नयी दिल्ली।**

पामेला है

'माया' (३० अप्रैल, १९८९) में प्रकाशित पामेला बोर्डेस की तस्वीर यकीनन पामेला की है। नाक, आंखें और होंठों को देखने से वह बिलकुल पामेला लगती है। पामेला कुंभ मेले में क्यों आयी, यह सवाल 'माया' ने ठीक ही उठाया है। सरकार को चाहिए कि वह इस पर जांच-पड़ताल करवाये, ताकि सही-सही जानकारी हो सके।**—अनूप 'सतनहा', धवारी-५, सतना, मप्र**

क्या अनिल कपूर अमिताभ को पीछे छोड़ जायेगा ?

'माया' (३० अप्रैल) में 'क्या अनिल कपूर अमिताभ को पीछे छोड़ जायेगा ?' लेख बेहद रोचक रहा। क्योंकि 'माया' ही एक ऐसी पत्रिका है जो हकीकत का सही-सही बयान करती है। साथ ही 'कक्काजी कहिन' छुटभैये नेताओं की असली तस्वीर प्रतीत होती है। इसमें शक नहीं कि ऐसे ही नेताओं के कारण समाज में बुराइयां फैलती हैं। **—महावीर चंद कोठारी, मुकुटबन, जी यवतमाल, महाराष्ट्र**

चोटी पर पहुंचने में माहिर थे बहुगुणा

'माया' ३० अप्रैल, १९८९ में पीडी टंडन का लेख 'चोटी पर पहुंचने में बहुगुणा माहिर थे' पढ़ने पर ऐसा लगता है कि पीडी टंडन स्वर्गीय बहुगुणाजी के साथ बीते हुए समय का वर्णन न करके उन्होंने केवल नेहरू परिवार और बहुगुणा की तारीफ के पुल बांधे हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि कई राजनीतिक हस्तियों की अस्थियां विसर्जित होते देखा है, मगर गांधी, नेहरू और इंदिरा को छोड़कर मैंने ऐसा गहरा गम कभी नहीं देखा, जैसाकि बहुगुणा के पार्थिव शरीर के बमरौली हवाई अड्डे पर उतरने के समय दिखायी पड़ा था। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या संजय गांधी की अंत्येष्टि-यात्रा में ऐसा दृश्य नहीं था ? एमजी रामचंद्रन की मृत्यु पर तो कितने लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी ! **—मनोज कुमार, बीएससी (इंजीनियरिंग), पटना**

जनता के नाम पर अपना महोत्सव

'माया' के १५ अप्रैल के अंक में 'अमेठी विज्ञान प्रदर्शनी : तीस करोड़ की होली' पढ़ा। आज गरीबी, बेरोजगारी जैसी अनेक जटिल समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं, परंतु इनके निदान हेतु सरकार का रुख मात्र दिखावा होता है। एक ओर गरीबों के खून जल रहे हों तथा दूसरी ओर नेतागण व्यर्थ का धन बर्बाद कर रहे हों, यह कहां तक उचित है ? एक ओर सरकार भूमिहीनों को भूमि देने का वादा करती है, तो दूसरी ओर सरकारी जमीन नेताओं की जागीर बनती जा रही है, क्या इससे देश का भविष्य गर्त में नहीं जायेगा ? अब भी हमारे ग्रामीण भाई कोसों की दूरी पैदल तय करते हैं, परंतु ये नेतागण व्यस्तता की आड़ में सौ मीटर की दूरी भी कारों द्वारा तय करते हैं। अत: ये सफेदपोश जनता के रक्षक न होकर भक्षक हैं और जनता भी अब समझ चुकी है। मन में पनपती द्वेष भावना ही छिटपुट घटनाओं के रूप में उग्रता धारण करती जा रही है जो एक दिन एक क्रांति का रूप अवश्य धरेगी।**—विजय कुमार, शिकारपुर, पटना सिटी**

अनोखा विवाह

३१ मार्च, १९८९ की 'माया' में अनोखे प्रेम विवाह ने लिखने पर विवश किया। मैं बुखार की हालत में पत्र लिख रही हूं। बुखार में ही वह समाचार पढ़ा था। वास्तव में यह साहसिक व अनोखा विवाह है। मंजु तथा मधु सहेलियां थीं, दोस्ती ठीक थी, पर एक ने अपना लिंग बदल लिया, यह विकृत मानसिकता है। विदेशों में क्या होता है, छोड़िए। ये दोनों अभी अवश्य प्रसन्न हैं, पर कुछ समय बाद ये स्वयं एक दूसरे से घृणा करने लगेंगी, तब आत्महत्या ही इनकी अंतिम परिणति होगी ! मधु को पति की बलिष्ठ बाहें चाहिए होंगी। मंजु की भी मानसिकता तो न बदली होगी शरीर के साथ। इन लड़कियों ने अपना भविष्य अंधकारित कर लिया। अभिभावक भी कुछ न कर सके। कुछ समय बाद आप ही उनकी दुखद कथा भी 'माया' में छापेंगे।**—मधु पटियाला, पंजाब**

निवेदन

'माया' अयाचित सामग्री स्वीकार नहीं करती है। अयाचित सामग्री के साथ समुचित डाक टिकट लगा लिफाफा नहीं होगा, तो उसे लौटाने की जिम्मेदारी भी 'माया' की नहीं होगी।—संपादक

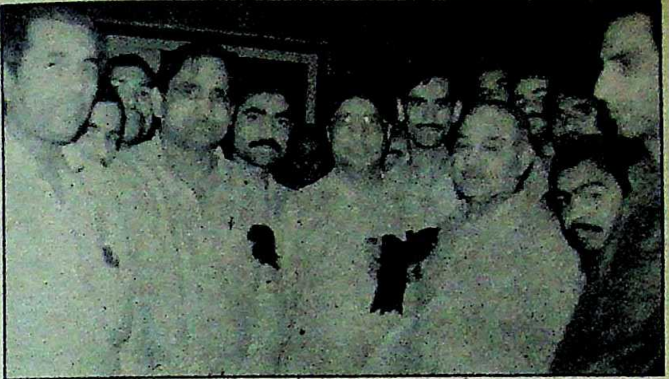

फिर टीवी किस काम आयेगा ?

पिछले दो सालों से विपक्ष का सारा जोर इस बात को सिद्ध करने में लगा हुआ था कि कांग्रेस-इ के आलानेता कितने भ्रष्ट और अनैतिक हैं। अब जहर को जहर से काटने का नुस्खा कांग्रेस-इ ने अपना लिया है। कर्नाटक सरकार को सुब्रह्मण्यम स्वामी के सौजन्य से पहले इसी मुद्दे के आधार पर बदनाम किया और अंत में फिर 'विधायकों की खरीद-फरोख्त के कारण उत्पन्न हुए संवैधानिक संकट' का आसरा लेकर वहां की सरकार को धराशायी कर दिया। हाल में यहां प्रकाशित चित्र को काफी तूल दिया गया है। टीवी पर तो इसका प्रदर्शन किया ही गया है, राज्यसभा में भी इसको लेकर ४५ मिनट तक धमाचौकड़ी मची है। इस चित्र के माध्यम से यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो जनतादल मूल्याधारित राजनीति की बात करता है, उसके नेता 'हीरोइन-तस्करों' के यहां चाय-पान करते हैं, उनके साथ मंच पर बैठते हैं।

दरअसल अजीत सिंह के बायीं ओर जो भारीभरकम महाशय खड़े हैं, उनका नाम नाजिर अली है। वे जब विधायक थे, तो उनके लखनऊ स्थित आवास (दारुलशफा) पर सीबीआई ने छापा डालकर दो करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी थी। ये महाशय शाहजहांपुर के रहनेवाले हैं, जहां ९ अप्रैल को जनता दल की एक सभा हुई थी। उस सभा-मंच पर वीपी सिंह, मेनका गांधी,अजीत सिंह, सत्यप्रकाश मालवीय और उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष सत्यपाल सिंह यादव के साथ नाजिर अली भी विराजमान थे। बाद में नाजिर अली ने चाय-दावत दी। उससे वीपी सिंह और मेनका गांधी तो बच निकले, लेकिन बाकी लोग उपस्थित थे। कहते हैं, वीपी सिंह को किसी पुलिसवाले ने नाजिर अली के बारे में याद दिला दिया था, इसलिए वे लखनऊ मेल पकड़ कर दिल्ली पहुंचने के बजाय कार से लखनऊ पहुंच गये। 'माया' को पता चला है कि गुप्तचरों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें लिखा है कि शाहजहांपुर में इन नेताओं ने १६ लाख रुपए एकत्र किये थे, जिनमें ११ लाख उस कार की डिक्की में थे जो वीपी सिंह को लेकर लखनऊ पहुंची थी और ५ लाख अजीत सिंह के सहयोगी अपने साथ लेकर आये थे। रकम के किस्से में तो कोई दम नहीं, लेकिन फोटो से उन्हें जनता दल को बदनाम करने और उसमें फूट डालने का मसाला मिल गया।

उल्लेखनीय बात यह है कि यह फोटो कांग्रेस खेमों तक जनता दल के नेताओं के सौजन्य से ही पहुंची है। जाहिर है, यह खेमा उन लोगों का दोस्त नहीं हो सकता जो फोटो में खड़े हैं। वैसे, यदि बदनाम लोगों के साथ फोटो खिंचवाने को ही अनैतिकता और भ्रष्टाचार का सबूत माना जाता है, तो ऐसे फोटो कांग्रेसी नेताओं के काफी छप चुके हैं। वीपी सिंह के चुनाव के समय इलाहाबाद के एक 'बाहुबली' बड़े-बड़े नेताओं के साथ मंच पर बैठे थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट थे, लेकिन पुलिस को वे नहीं दिखायी पड़ रहे थे। उनके फोटो भी छपे थे। यह बात दूसरी है कि उन चित्रों को न टीवी पर दिखाया गया, न उनको लेकर लोकसभा-राज्यसभा में हंगामा हुआ। लगता है, अगले चुनाव तक पक्ष-विपक्ष में यही जायज-नाजायज तरीकों से सिद्ध करने की ज्यादा होड़ रहेगी कि कौन कितना बड़ा भ्रष्ट और अनैतिक है, ताकि एक दूसरे पर आरोप लगाने से पहले वे अपने गरेबान में झांक कर देख लें। लेकिन पक्ष, विपक्ष के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल करे, तो बात समझ में आती है, लेकिन विपक्ष का एक महारथी यदि दूसरे महारथी को मारने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करता है, तो विपक्ष का खुदा ही मालिक है। इस समय कांग्रेस-इ को ऐसे स्कैंडलों की बेहद जरूरत है। उसके पास टीवी जैसा देशव्यापी दृश्य-श्रव्यं माध्यम है ही, इन सब स्कैंडलों को उछालने के लिए। ■

◆ खयालात

राजीव गांधी आदतन झूठे हैं। –**रामकृष्ण हेगड़े**

कर्नाटक की जनता दल सरकार के कत्ल में राज्यपाल ने जितनी निम्न स्तर की भूमिका निभायी है, वैसी तो किसी कंपनी का एजेंट भी नहीं निभाता।—**जनता दल सांसद जयपाल रेड्डी, दिल्ली में।**

अगर आज अंबेडकर होते, तो कर्नाटक के मुद्दे पर यही कहते कि संविधान के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है।—**अगप सांसद दिनेश गोस्वामी, लोकसभा में।**

मैं केंद्र सरकार के हाथ नहीं, संविधान के हाथ में खेलता हूं।—**राज्यपाल वेंकटसुबैया, बंगलौर में।**

जनता दल राजीवरहित कांग्रेस-इ का 'डुप्लीकेट' (नकल) है।—**जपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी।**

डा० स्वामी उस श्रेणी के लोगों में आते हैं जो ऊटपटांग तस्वीरें बना-बनाकर घर की सीढ़ियां और शौचालय की दीवारें गंदी करते रहते हैं।—**रामकृष्ण हेगड़े।**

जब कोई रिपोर्ट 'लीक' हो जाती है, तब सरकार रिपोर्ट पर विचार करना छोड़ देती है, 'लीक' पर ही विचार करती है।—**शरद जोशी, 'नवभारत टाइम्स' में।**

ठक्कर आयोग रिपोर्ट को देशवासियों से छिपाये रखने की साजिश पर परदा डालने के लिए, बूटा सिंह शायद एक और साजिश में जुट गये हैं।—**अरुण नेहरू।**

राजीव सरकार ने आज सिखों को बलि का बकरा बना रखा है—कल दलितों, मुसलमानों या ब्राह्मणों को भी बनायेगी।—**लेखक महीप सिंह।**

भाकपा के नेतृत्व को बुढ़ापे ने ग्रस रखा है।—**भाकपा की (कलकत्ता कांग्रेस में प्रस्तुत) 'संगठन रिपोर्ट'।**

इंदिरा गांधी की हत्या का मामला अगले चुनाव का भी अव्वल मुद्दा बनेगा—तब यह कांग्रेस-इ के पक्ष में रहा था, अब हमारी तरफ रहेगा।—**प्रो० मधु दंडवते।**

भारत में विपक्ष का चरित्र विचित्र है। वह चोटी के कांग्रेसी नेताओं में से, उनकी तारीफ करता है जो मर गये और उनकी निंदा करता है जो जीवित हैं।—**एचकेएल भगत।**

वह भाजपा ही है जो भाकपा और वामपंथ के खिलाफ कांग्रेस-इ से गांठ जोड़ रही है।—**हरकिशन सिंह सुरजीत, दिल्ली में।**

फिल्म में इन जुड़वां अश्लीलताओं-सेक्स और हिंसा-की नुमाइश अब एकदम बंद की जाये।—**राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमन, मद्रास में।**

धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक धोखाधड़ी है।—**प्रसिद्ध विधिवेत्ता राम जेठमलानी, कलकत्ता (संगोष्ठी) में।**

आप (बूटा सिंह) के पास दिमाग कैशियस का है और हाथ लेडी मैकबेथ के।—**एमएस गुरुपदस्वामी**

बूटा की समझ में 'लेडी' तो आ सकती है, पर मैकबेथ नहीं।—**एजी कुलकर्णी, दिल्ली में।**

मुझे नहीं पता कि जनता दल में क्या हो रहा है, न मेरी इसमें दिलचस्पी है। मेरी दिलचस्पी तो अंतिम परिणाम में है।—**चंद्रशेखर 'द इंडियन पोस्ट' में।**

अगर भारत तकरार पर उतर आये, तो नेपाल की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया तो होगी ही!—**नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एमपी कोइराला, इंडियन एक्सप्रेस में।**

तूफ़ानी रात का आपके सोते हुए
यात्रियों को पता भी न चले!

विक्रांत
एक भरोसेमंद टायर

जो उसी तकनोलॉजी से बना है जिसने
भारत के सर्वप्रथम ट्रक रेडियल टायर बनाए!

MAA COMMUNICATIONS VTL 588A HIN

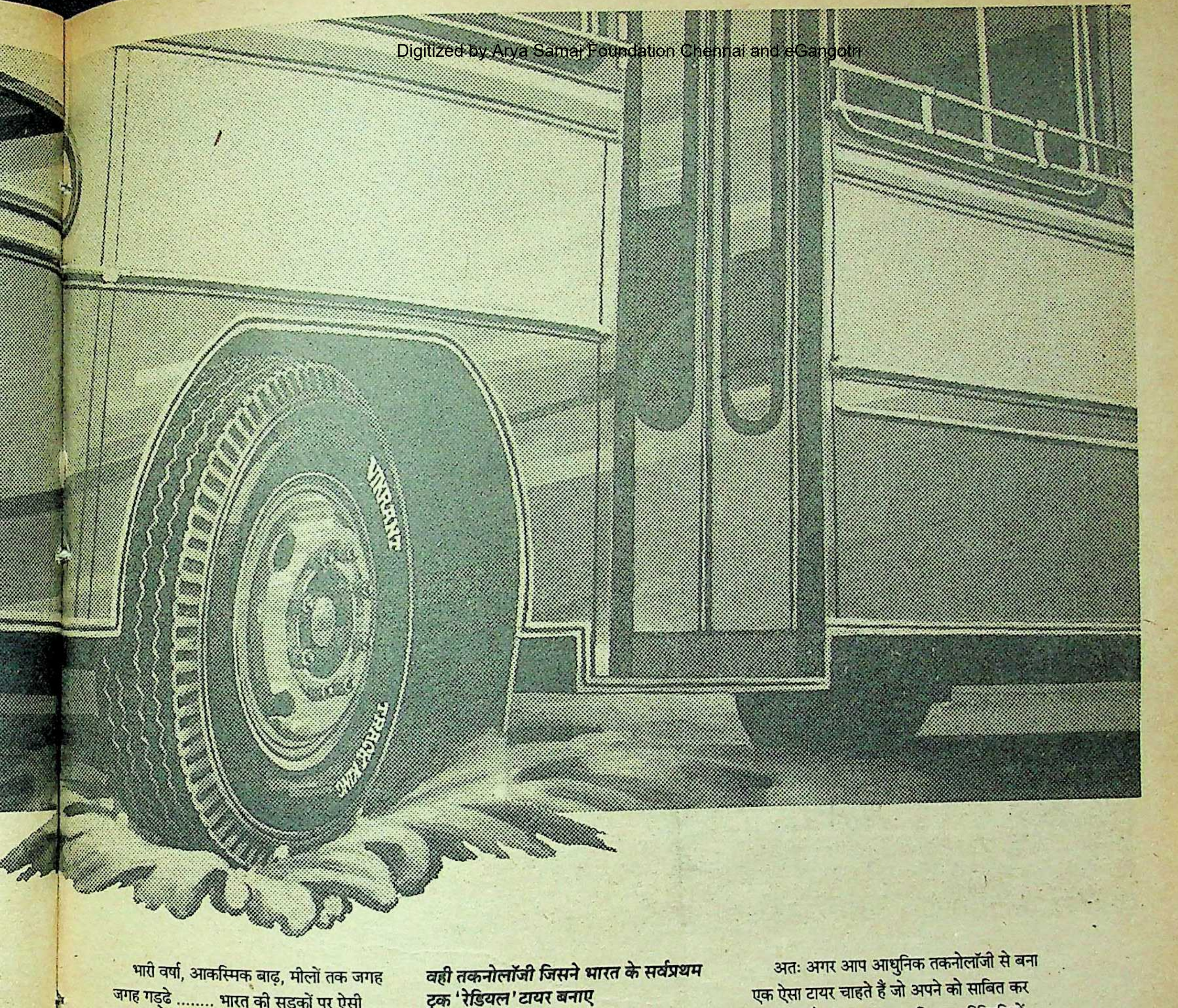

भारी वर्षा, आकस्मिक बाढ़, मीलों तक जगह जगह गड्ढे .... भारत की सड़कों पर ऐसी परिस्थितियाँ एक आम बात हैं । एक टायर विशेष रूप से ऐसी ही आकस्मिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है जो हज़ारों मील तक आपके प्रत्येक यात्री को सुरक्षित ले जाता है । और वह है विक्रांत - एक भरोसेमन्द टायर जिसे बनाने वाली आधुनिक तकनोलॉजी का उपयोग भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

विश्व की सर्वोत्तम ' रेसिंग टायर तकनोलॉजी'

हर विक्रांत टायर को बनाने में ब्रिटेन की ' एवॉन ' कम्पनी की तकनीकी उत्तमता का हाथ है । रेसिंग टायरों में प्रथम स्थान प्राप्त ' एवॉन ' से ही वाहनों के सरताज —'रोल्स रॉएस'— अपनी अधिक्तम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं । विक्रांत का ' अनुसंधान और विकास ' विभाग इसी ' एवॉन ' तकनोलॉजी में आवश्यक सुधार कर इसे भारतीय सड़कों के अनुरूप ढालता है ।

वही तकनोलॉजी जिसने भारत के सर्वप्रथम ट्रक 'रेडियल' टायर बनाए

जब विक्रांत के ' अनुसंधान और विकास' विभाग ने अपना ध्यान ट्रकों के लिए 'रेडियल'टायर बनाने पर केन्द्रित किया तो उसका परिणाम था एक ऐसा शक्तिशाली टायर जिसने फ़ौरन अपना स्थान ब्रिटिश बाज़ार में बना लिया। और इस तरह विक्रांत ट्रकों के लिए 'रेडियल' टायर बनाने व उसे ब्रिटेन निर्यात करने वाली भारत की सर्वप्रथम कम्पनी बनी।

विक्रांत — उच्च श्रेणी के वाहनों का मूल उपकरण

विक्रांत ने अपने काम द्वारा सम्पूर्ण परिवहन उद्योग में अपनी विश्वसनीयता को साबित कर दिया है । इसीलिए यह ' टैल्को ' और ' अशोक लेलैण्ड ' जैसी उच्च श्रेणी की कम्पनियों द्वारा निर्मित वाहनों के लिए मूल उपकरण के रूप में चुना जाता है । साथ ही यह अधिक्तम राज्य परिवहन निगमों की बसों में रोज़ हज़ारों लोगों को देश भर में जगह जगह ले जाता है ।

अतः अगर आप आधुनिक तकनोलॉजी से बना एक ऐसा टायर चाहते हैं जो अपने को साबित कर चुका हो और जिसपर आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भरोसा कर सकें तो स्पष्ट है आप सिर्फ़ विक्रांत को ही चुनेंगे ।

VIKRANT

भरोसेमंद टायर
ज़िम्मेदार कम्पनी

बूटा की करामात

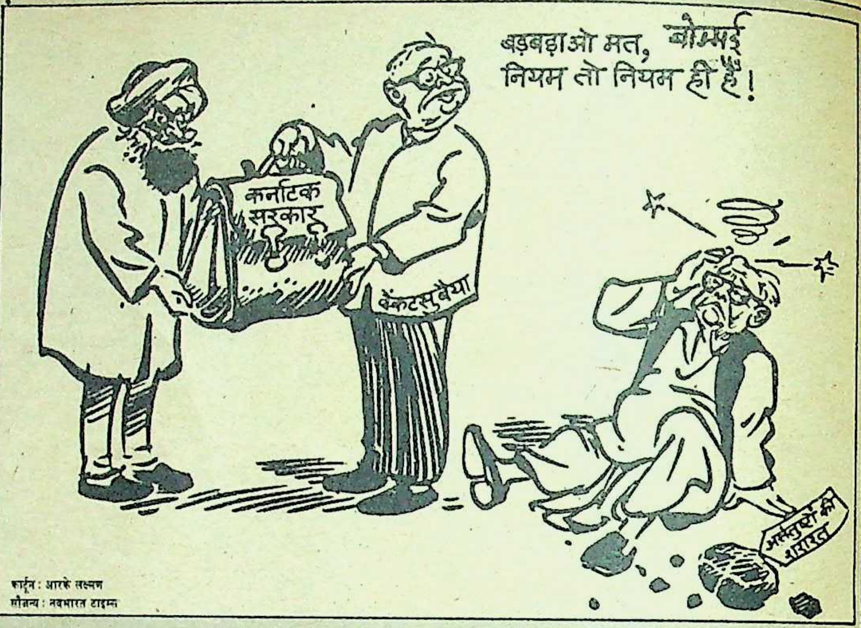

कार्टून : आरके लक्ष्मण
सौजन्य : नवभारत टाइम्स

बूटा सिंह वेंकटसुबैया (कर्नाटक के राज्यपाल) से फोन पर बतिया कर पंचम में दहाड़े, "बोले सो निहाल...।" पास खड़े कल्याणकृष्णन (केंद्रीय गृह सचिव) ने उनके कान में आहिस्ता से कहा, "सर, गर्वनर की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ बोलें, तो नियमानुसार रहेगा। आफ्टर आल, आप मुल्क के होम मिनिस्टर भी हैं।" बूटा सिंह ने अपना मुंह बंद करके उस पर चुप्पी के लिए उंगली रख ली। वे नार्थ ब्लाक से निकल कर दिल्ली दरबार के साउथ ब्लाक की तरफ रवाना हुए, तो उनकी कार के आगे चलनेवाली पायलट कार का सायरन दुगनी आवाज से 'सांय...सांय...' कर रहा था और लाल-पीली-नीली बत्तियां चौगुना स्पार्क मार रही थीं।

१८ अप्रैल को दिल्ली दरबार में कर्नाटकी संगीत की महफिल जमी हुई थी। जाफर शरीफ, जनार्दन पुजारी और आस्कर फर्नांडीस बगलें बजा-बजा कर संगति कर रहे थे। इसी बीच 'बल्ले-बल्ले' करके मटकते हुए आदरणीय बूटा सिंह नमूदार हुए। बूटा सिंह दरबार की तरफ मुखातिब हो गये, "हुजूर, बोलिए बोम्मई (सरकार) की गरदन मेरे हाथ में है। उसे मार दिया जाये या छोड़ दिया जाये!" दिल्ली दरबार बड़े ही तटस्थ भाव से देख रहे थे कि पीछे से संतोष मोहन देव (गृह राज्यमंत्री) ने टू-इन-वन पर टेप फिट कर दिया, "बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाये, मार दिया जाये या छोड़ दिया जाये।" इतने में ही आरके धवन हाथ में वीडियो कैसेट लेकर जब दरबार के सामने हाजिर हुए, तो बूटा सिंह को पसीना छूटने लगा। धवन ने दरबार के कान में कहा, "सर, बोम्मई (सरकार) की 'नेचुरल डेथ' हो रही है। सारे-के-सारे जनता दलीय नेता उसकी मौत का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग दरबार में इस बात का 'क्रेडिट' लेने की फिराक में हैं कि बोम्मई की गरदन वे मरोड़ रहे हैं।" दरबार ने सुनने के बाद भी जब अपने चेहरे के तटस्थ भाव को पूर्ववत बनाये रखा, तो धवन को भी पसीना आ गया। दूसरी ओर बूटा सिंह गुरुगंभीर मुद्रा में दरबार की तरफ मुखातिब हो गये, "सर, मैंने भी पब्लिक पोस्चर यही ले रखा है कि बोम्मई की 'नेचुरल डेथ' हो रही है। लेकिन हकीकत तो आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले तक कई विपक्षी राज्य सरकारों को गिराने की योजना हम लोगों ने बना रखी है। इसके लिए हम लोगों ने सीआईए और केजीबी, दोनों टेक्नोलाजियां आयात कर रखी हैं।" धवन ने बात काटने की कोशिश की, तो बूटा सिंह ने अपना स्वर ऊंचा कर दिया, "सर, जिसे दरबार में 'नेचुरल डेथ' कह कर परिभाषित किया जा रहा है, उसके पीछे इस नामुराद सेवक का भेजा (मस्तिष्क) है। हमने एक लंबे अरसे से आईबी को नयी सीआईए तथा केजीबी टेक्नोलाजी से लैस करके बंगलौर और दिल्ली में लगा रखा है। आपकी अनुमति से जैम्सबांड ००५ यानी सुब्रह्मण्यम स्वामी की सेवाएं ले रखी हैं। ठीक है, बाहर तो हमको यही दिखाना है कि बोम्मई की 'नेचुरल डेथ' हुई है। लेकिन घर (दरबार) में इसका 'क्रेडिट' तो मुझे मिलना ही चाहिए।" धवन ने देखा कि बूटा सिंह को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने पास रखे वीडियो में कैसेट घुसेड़ दिया। बूटा सिंह की बोलती तुरंत बंद हो गयी। दरबार के चेहरे पर पूर्ववत तटस्थ भाव ही रहा, लेकिन उन्होंने अपनी निगाहें वीडियो स्क्रीन पर जमा लीं...

...रामकृष्ण हेगड़े ने अपनी खिचड़ी दाढ़ी खुजलाई और सोफे पर बैठते हुए अपने समर्थक विधायकों के कान करीब करने का इशारा करते हुए फुसफुसा कर बोले, "बोम्मई अपनी जान बचाने के लिए कीचड़ में गले तक धंसी मेरी 'इमेज' को निकालने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहा है। इसको एक गहरा धक्का लगना जरूरी है।" हेगड़े के एक समर्थक विधायक ने कहा, "गुरु, पिछले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही उसके प्राण हथेली में आ चुके हैं। अगर गहरा धक्का मारा, तो प्राण पखेरू ही कहीं न उसके उड़ जायें?" हेगड़े ने दाढ़ी खुजलाने के साथ अपनी आंख भी मटकायी, "बोम्मई के प्राण पखेरू उड़ जाते हैं, तो उड़ जाने दो। मेरे तो प्राण बच जायेंगे।" एक समर्थक विधायक ने पूछा, "बोम्मई के प्राण पखेरू उड़े, तो तुम्हारे प्राण कैसे बचेंगे?" हेगड़े ने दाढ़ी का सफेद बाल उखाड़कर उस विधायक के हाथ में रख दिया, "बोम्मई की सरकार अगर गिर जाती है, तो कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। उस समय अगर मेरे ऊपर कोई जांच बिठायी गयी, तो हम लोग चिल्लायेंगे कि केंद्र बदले की भावना से मेरा चरित्र-हनन कर रहा है। देखो, यों तो मेरी भी कोई 'क्रेडीबिलिटी' नहीं है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली दरबार की भी मेरी जैसी ही हालत है। जनता बहुत भोली होती है। वह हमेशा समर्थ के खिलाफ ही जाती है। उस समय मैं असमर्थ होऊंगा। जनता मेरे साथ होगी।" समर्थक विधायकों ने 'हेगड़े दर्शन' सुनने के बाद बगलें झांकना शुरू कर दिया। हेगड़े समझ गये कि विधायक पूछ रहे हैं कि उनको इससे क्या मिलेगा? वे चट से उठे और अपने सूटकेस की चाबी उनको थमाते हुए बोले, "प्यारो, मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा!" एक समर्थक विधायक चाबी लेने के बाद बोला, "सुब्रह्मण्यम स्वामी तो कह रहा है कि तुमने चीफ मिनिस्टरी में करोड़ों के वारे-न्यारे किये। लेकिन यह सूटकेस तो काफी हलका लग रहा है।" हेगड़े ने इस बार दाढ़ी कम खुजलायी और मुस्कराहट ज्यादा मारी, "सब ठीक हो जायेगा। स्वामी काफी बढ़कर हांक रहा है। उससे मैंने कहा था कि कुछ ले-दे कर चुप हो जाओ। लेकिन वह दिल्ली दरबार से जा मिला। ठीक है। उसे तो हम देख लेंगे। फिलहाल तुम १६ विधायक गवर्नर से मिलकर बोम्मई को डराओ। शायद वह कब्जे में आ जाये।"

...दिल्ली दरबार ने कनखियों से बूटा सिंह की तरफ देखा, लेकिन अपने तटस्थ भाव को चेहरे से बिखरने नहीं दिया। बूटा सिंह को ठंडा पसीना आया, लेकिन उन्होंने अपनी कंपकंपी को रोक लिया। तब तक वीडियो स्क्रीन पर राजा मांडा (वीपी सिंह) चढ़े हुए थे...आरिफ ने कोशिश की कि वे राजा मांडा के होंठों से बांसुरी खींच लें, लेकिन अरुण नेहरू ने आरिफ को रोक लिया, "क्यों रोक रहे हो आरिफ मियां विश्वनाथ को? बजाने दो उसे बांसुरी। बहुत दिनों बाद वह चैन की बांसुरी बजा रहा है।" आरिफ नें कहा, "बोम्मई सरकार मरणासन्न स्थिति में पड़ी हुई है। राजा का चैन की बांसुरी बजाना ठीक नहीं है, अरुण भाई। गवर्नर सुबैया ने रिपोर्ट भेज दी है कि...।" अरुण नेहरू ने आरिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, "इसमें राजा क्या कर सकता है? बोम्मई सरकार को दिल्ली दरबार थोड़े ही गिरा रहा है कि राजा गरजे। अरे उसको तो मार रहे हैं उसके अपने ही लोग। किसी के घर के झगड़े में पड़ना ठीक नहीं है। जनता दलवाले उससे निपटेंगे। वह चंद्रशेखर भौंडसी में बैठा सांड़ों का दूध दुह रहा है। उसने देवगौड़ा को केवल इतना कहला दिया कि बोम्मई की सरकार नहीं गिरनी चाहिए। अरे बोम्मई सरकार गिर जाने के बाद हमारी और राजा की स्थिति और मजबूत होगी। उस ताऊ (देवीलाल) की सरकार भी गिर जाये, तो सारे-के-सारे अपनी औकात पर आ जायेंगे।" आरिफ अरुण नेहरू का मुंह ताक कर रह गये। राजा मांडा चैन की बांसुरी बजाने में जुटे रहे। ...

धवन ने आगे बढ़कर वीडियो बंद कर दिया। बूटा सिंह और धवन, दोनों उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली दरबार के चेहरे पर भाव बदलेंगे। लेकिन उनके चेहरे पर 'तटस्थ भाव' ही बना रहा। दरबार के उठते ही फिर गाना शुरू हो गया, "बोल तेरे साथ बोम्मई क्या सलूक किया जाये, मार दिया जाये या छोड़ दिया जाये!" दरबार के तटस्थ भाव से उठने के बाद कर्नाटकी कन्नड़ में चिल्लाये, "बोम्मई को 'नेचुरल डेथ' से मरने दो।" लेकिन बूटा सिंह ने उसी समय मंच संभाल लिया "आप लोगों को पब्लिक में यही कहना है कि बोम्मई की 'नेचुरल डेथ' हुई है। लेकिन राजनीति में 'नेचुरल डेथ' का कोई मतलब नहीं होता है। सत्तातंत्र बड़ा बेरहम होता है। जब सत्ता पुरुष कमजोर हो, तो उसे कभी भी अपनी कमजोरी उजागर नहीं करनी चाहिए। अब तो जनता दल ने ही अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया है। इसलिए एक बार हम चाहें भी कि बोम्मई की 'नेचुरल डेथ' हो, तो भी नहीं हो सकती है। सत्तातंत्र की तटस्थ प्रक्रिया शुरू हो गयी। गर्वनर की रिपोर्ट आं चुकी है। सत्तातंत्र तटस्थ भाव से बोम्मई को निगल जायेगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। राजनीति का यही अभिशाप १९७७ में हमने भोगा था। आज जनता दल को भोगना पड़ेगा। सत्तातंत्र बोम्मई सरकार की हत्या किये बिना नहीं रह सकता है। वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा।"

—दरबारी लाल

बूटा सिंह ने अपना स्वर ऊंचा कर दिया, "सर, जिसे दरबार में 'नेचुरल डेथ' कह कर परिभाषित किया जा रहा है, उसके पीछे इस नामुराद सेवक का भेजा (मस्तिष्क) है। हमने एक लंबे अरसे से आईबी को नयी सीआईए तथा केजीबी टेक्नोलाजी से लैस करके बंगलौर और दिल्ली में लगा रखा है। आपकी अनुमति से जैम्सबांड ००५ यानी सुब्रह्मण्यम स्वामी की सेवाएं ले रखी हैं।

बूटा सिंह ने उसी समय मंच संभाल लिया, "आप लोगों को पब्लिक में यही कहना है कि बोम्मई की 'नेचुरल डेथ' हुई है। लेकिन राजनीति में 'नेचुरल डेथ' का कोई मतलब नहीं होता है। सत्तातंत्र बड़ा बेरहम होता है। जब सत्ता पुरुष कमजोर हो, तो उसे कभी भी अपनी कमजोरी उजागर नहीं करनी चाहिए। अब तो जनता दल ने ही अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया है।

गुजरात के नये मुख्यमंत्री !

अगर गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी को हटाया जाता है, तो केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री बीके गढ़वी को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर गुजरात की मुख्यमंत्री-विरोधी-लाबी की तरफ से बहुत जोर डाला गया कि अमर सिंह चौधरी के संबंध में बहुत जल्दी फैसला किया जाये। राजीव गांधी ने केंद्रीय खान मंत्री माखनलाल फोतेदार को बुलाया और कहा कि आप तुरंत गुजरात जाकर स्थिति का जायजा लें। फोतेदार ने पहले आनाकानी की, लेकिन अंततः वे जाने के लिए तैयार हो गये। इसी बातचीत के दौरान फोतेदार ने कहा कि चौधरी की जगह कोई लायक मुख्यमंत्री तलाश करना काफी मुश्किल है। इस पर राजीव गांधी ने कहा कि मुझे कुछ लोगों ने बीके गढवी का नाम सुझाया है। आप यह भी देखें कि गढवी को गुजरात में क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है ? फोतेदार परेशानी में फंस गये। फोतेदार का वरदहस्त अमर सिंह चौधरी पर है। चौधरी को मुख्यमंत्री बनाये रखने के पीछे फोतेदार का सबसे सशक्त तर्क यही है कि पूरे देश में अमर सिंह चौधरी ही एक मात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उनको हटाया जाना उचित नहीं है।

प्रधानमंत्री के निर्देश पर फोतेदार को पिछले दिनों अहमदाबाद जाना पड़ा। वे एक दिन के लिए वहां गये, तो उनके सामने बड़ी समस्या पैदा हो गयी। वहां उनको हर तरफ अमर सिंह चौधरी का विरोध दिखायी पड़ा। वे अहमदाबाद से बिना कुछ किये दिल्ली वापस लौट आये और असंतुष्टों को दिल्ली में आकर मिलने के लिए कहा। गुजरात के असंतुष्ट दिल्ली में फोतेदार से आकर मिले। लेकिन फोतेदार ने उनको फटकार दिया। पता चला है कि फोतेदार ने पार्टी हाईकमान को अपनी यही रिपोर्ट दी है कि गुजरात में अमर सिंह चौधरी को कतई नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली में केंद्रीय योजना मंत्री माधव सिंह सोलंकी, पूर्व प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष अहमद पटेल आदि की तरफ से बराबर दबाव बना हुआ है कि अमर सिंह चौधरी को बदला जाये। बीके गढ़वी सोलंकी के खास आदमियों में से हैं।

प्रेस क्लब का मजाक

एक पत्रकार के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी लकदक 'खादी' के कवच से सज्जित सूरमा है जो विधवाओं और उपेक्षितों का उद्धार करते हैं। इस कार्य को अंजाम देते हुए उन्होंने राजीव दरबार के एक अन्य शूरवीर को भी परास्त कर दिया है। पत्रकार ने खुलासा करते हुए कहा : "विधवा कमला बहुगुणा है, उपेक्षित रामनरेश यादव हैं और राजीव दरबार के शूरवीर हैं वीर बहादुर सिंह।"

अरुण नेहरू की तैयारी

चैक पिस्तौलों के कथित घोटाले के संबंध में सीबीआई ने अरुण नेहरू से पूछताछ शुरू कर दी है। दो घंटे की पूछताछ के बाद कहते हैं प्रधानमंत्री सचिवालय में उच्चस्तर पर यह विचार-विमर्श चल रहा है कि यह छानबीन जारी रखी जाये या फिलहाल स्थगित कर दी जाये। इसका कारण यह बताया जाता है कि नेहरू ने अपनी गिरफ्तारी और अपने पर लगनेवाले भ्रष्टाचार के आरोपों की आशंका को देखते हुए ऐसी तैयारी की है कि जब सीबीआई उनसे दुबारा पूछताछ के लिए आये, तो वे ऐसा भंडाफोड़ करें कि उससे स्वयं प्रधानमंत्री को लेने-के-देने पड़ जायें।

पहली ही पूछताछ में नेहरू ने स्नैम प्रोजेटी के प्रतिनिधि इटलीवासी क्वात्रोची का नाम उछाल कर यह कहा है कि वे प्रधानमंत्री आवास में ढेर सारे ऐसे विदेशियों के साथ आया करते थे, जिनकी पृष्ठभूमि संदिग्ध थी। यह तो मात्र एक बानगी बतायी जाती है। कहते हैं यदि पिस्तौल घोटाले में उन्हें आगे और घसीटा गया, तो वे राजीव गांधी, सोनिया गांधी. बूटा सिंह और सतीश शर्मा तथा अन्य दिग्गजों को भी घसीट लेंगे। यह पिस्तौल घोटाला शायद वैसी ही स्थिति उत्पन्न करे जो शीशे के घरों में रहनेवालों के द्वारा दूसरे के घरों पर पत्थर फेंकने से उत्पन्न होती है।

◆

ओसवाल की खुशनसीबी

यह केवल इत्तफाक नहीं है कि महाराष्ट्र के एक सांसद के आवास पर आलीशान दावत के बाद राजीव गांधी के नये कृपापात्र अभय ओसवाल को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक खाद कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस मिल गया। सूत्रों के अनुसार पार्टी में ओसवाल के अलावा कुछ सांसद और स्नैम प्रोजेटी का एक प्रतिनिधि भी शामिल था। ओसवाल की उपस्थिति को देखकर एक सांसद को अचंभा हुआ था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वास्तव में यह जश्नी पार्टी थी।

अचंभे की बात यह है कि संबंधित मंत्री आर प्रभु को इस फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे अभी तक इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह लाइसेंस सार्वजनिक क्षेत्र को मिलना चाहिए। ओसवाल की खुशनसीबी के बारे में आरके धवन ने नारायण दत्त तिवारी को पहले ही सूचित कर दिया था।

◆

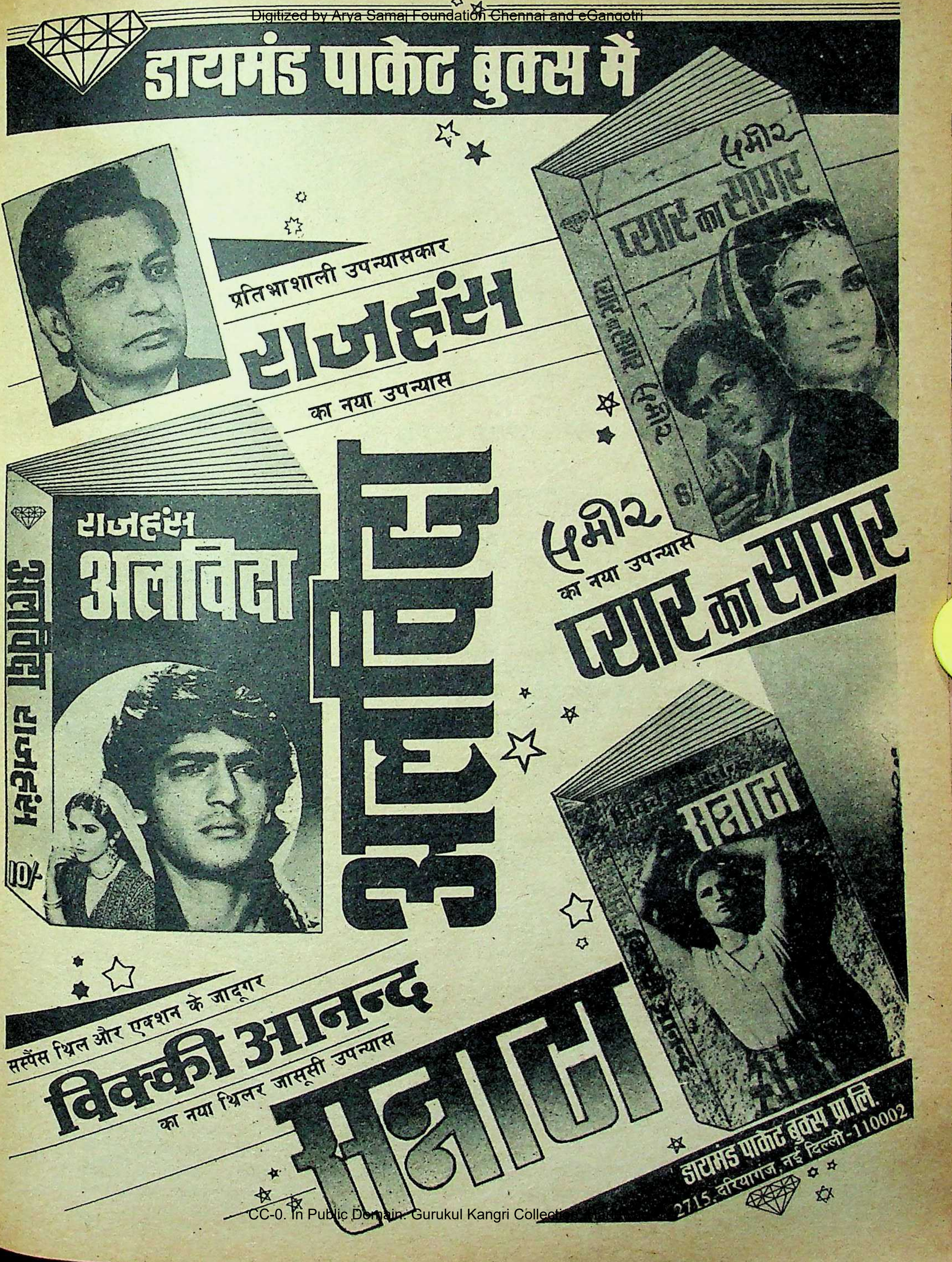
राजहंस
अलविदा
10/-
समीर
प्यार का सागर
सन्नाटा

डायमंड पाकेट बुक्स में

प्रतिभाशाली उपन्यासकार

राजहंस

का नया उपन्यास

अलविदा

समीर

का नया उपन्यास

प्यार का सागर

सस्पैंस थ्रिल और एक्शन के जादूगर

विक्की आनन्द

का नया थ्रिलर जासूसी उपन्यास

सन्नाटा

डायमंड पाकेट बुक्स प्रा. लि.
2715, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

अपने शिशु को प्रोटीन से भरपूर अंडे की पोषकता दीजिए

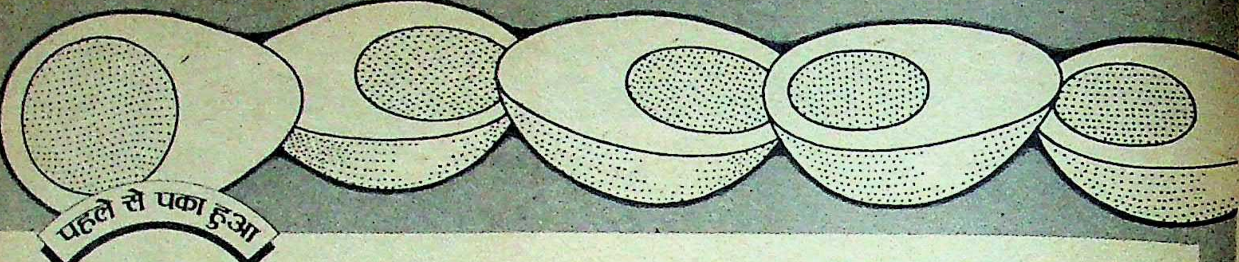

फ़ैरेक्स®-एग

६ठे महीने से...

नए फ़ैरेक्स-एग में है प्रोटीन. आपके शिशु के चहुमुखी विकास के लिए जिसकी ज़रूरत है.
यह पहले से ही पका हुआ है इसलिए शिशु की कोमल पाचन शक्ति के अनुकूल है.

फ़ैरेक्स. स्वाद भी पाए, बढ़ता भी जाए... मुन्ना.

PROTEIN-RICH
Farex-egg®
WITH CEREAL, EGGS AND MILK

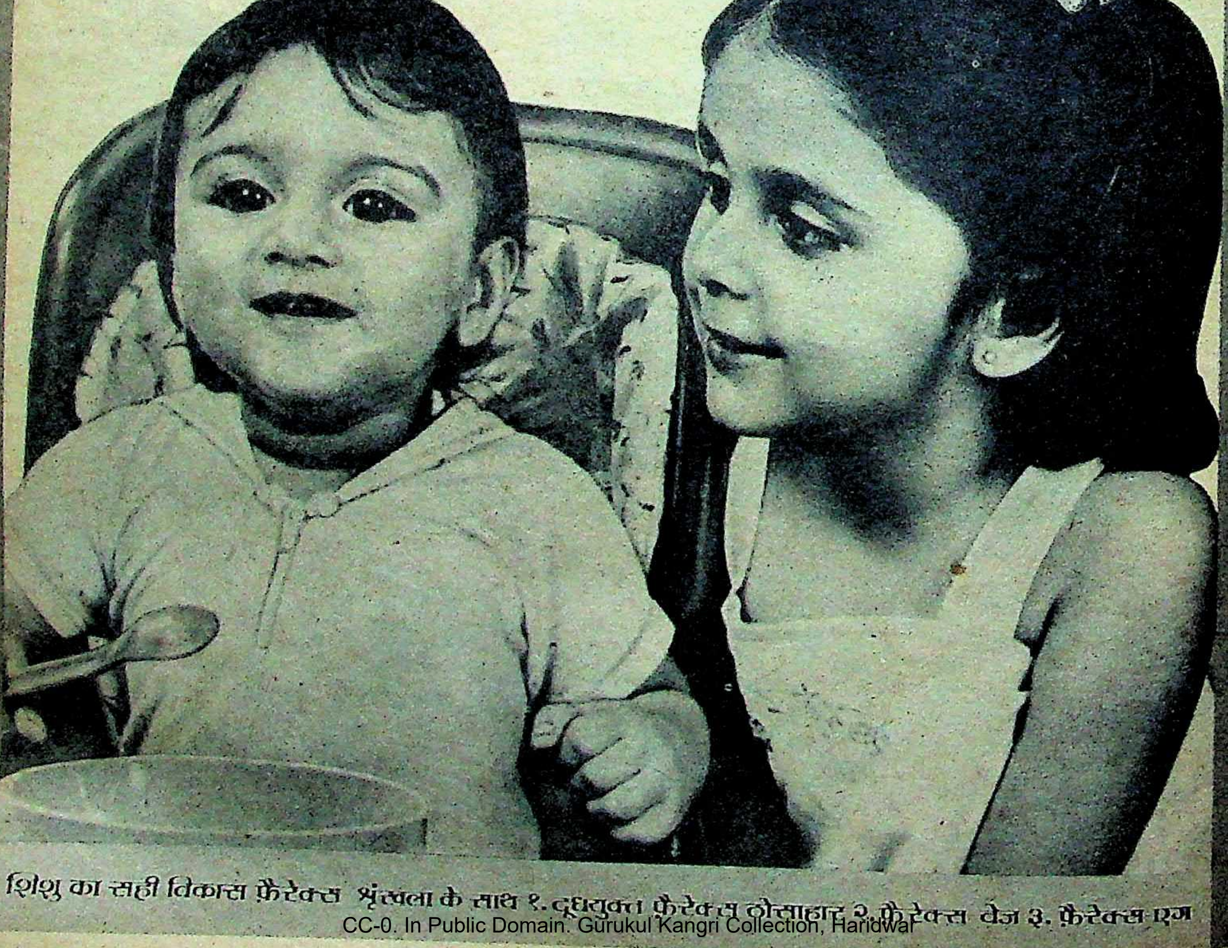

शिशु का सही विकास फ़ैरेक्स श्रृंखला के साथ १. दूधयुक्त फ़ैरेक्स ठोसाहार २. फ़ैरेक्स वेज ३. फ़ैरेक्स-एग

GX/32/254 HIN

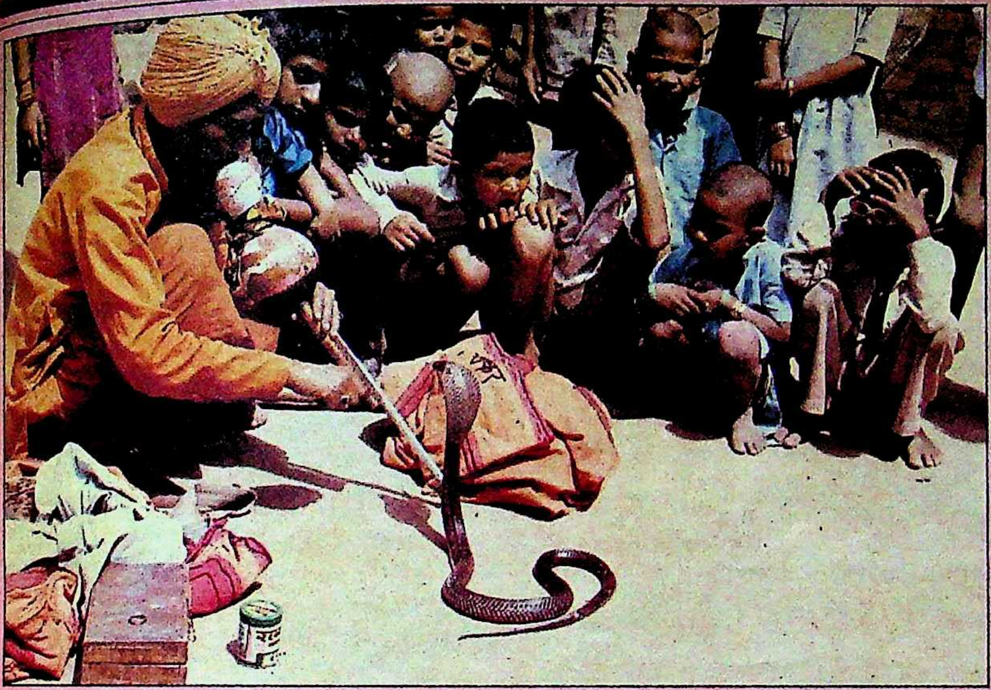

संपेरे बनने के लिए अभिशप्त: एक संपेरा बच्चों को बचपन से ही सांप को साथी और रोजगार का जरिया बनाने का प्रशिक्षण देते हुए

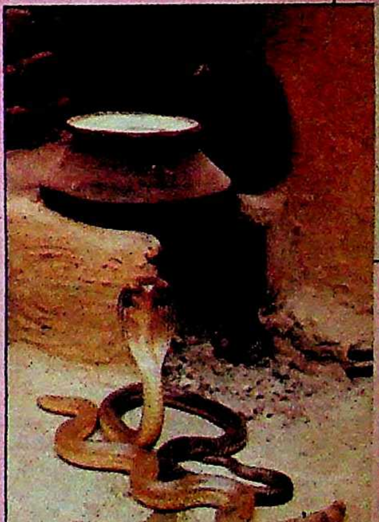

दूध पी कर दूध की रखवाली: सांप जहां परिवार का अभिन्न अंग है

सांप जिनका खिलौना है

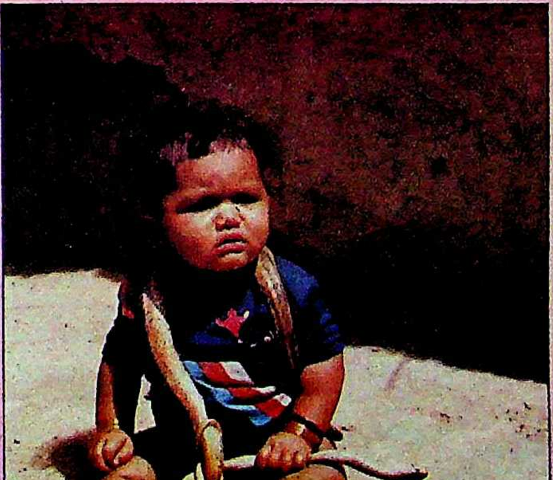

मोलड़बंद

संपेरों की बस्ती

सांप के नाम से ही रूह कांपने लगती है। उनके साथ रहना, सोना और बच्चों को उनसे खिलौनों की तरह खेलने देना, तो कल्पना के बाहर की चीज है। लेकिन यह कल्पना नहीं, हकीकत है कि एक पूरा गांव ऐसा है जहां मनुष्यों के साथ किसिम-किसिम के सांप भी स्थायीवासी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सांप निरापद हैं। उनमें विषैले-से-विषैले और डरावने-से-डरावने सांप हैं जिनको सरपट दौड़ते, कुंडली मारे, फन उठाये और फुंफकारते हुए देखने मात्र से बाहर के आदमी की हवा खुश्क हो सकती है।

लेकिन यह शौक नहीं, रोजी-रोटी का जरिया है और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से है। पीढ़ियों-की-पीढ़ियां सांपों को पालते, बीन की धुन पर उनको नचाकर पेट पालते हुए गुजर गयी हैं। यह बात दूसरी है कि अब देहात तक में मनोरंजन के इलेक्ट्रोनिक साधन पहुंच गये हैं और सांपों के जरिये पेट पालना संभव नहीं रहा है। लेकिन जीविका के वैकल्पिक

पिटारा उठाकर धंधे पर चलने की तैयारी

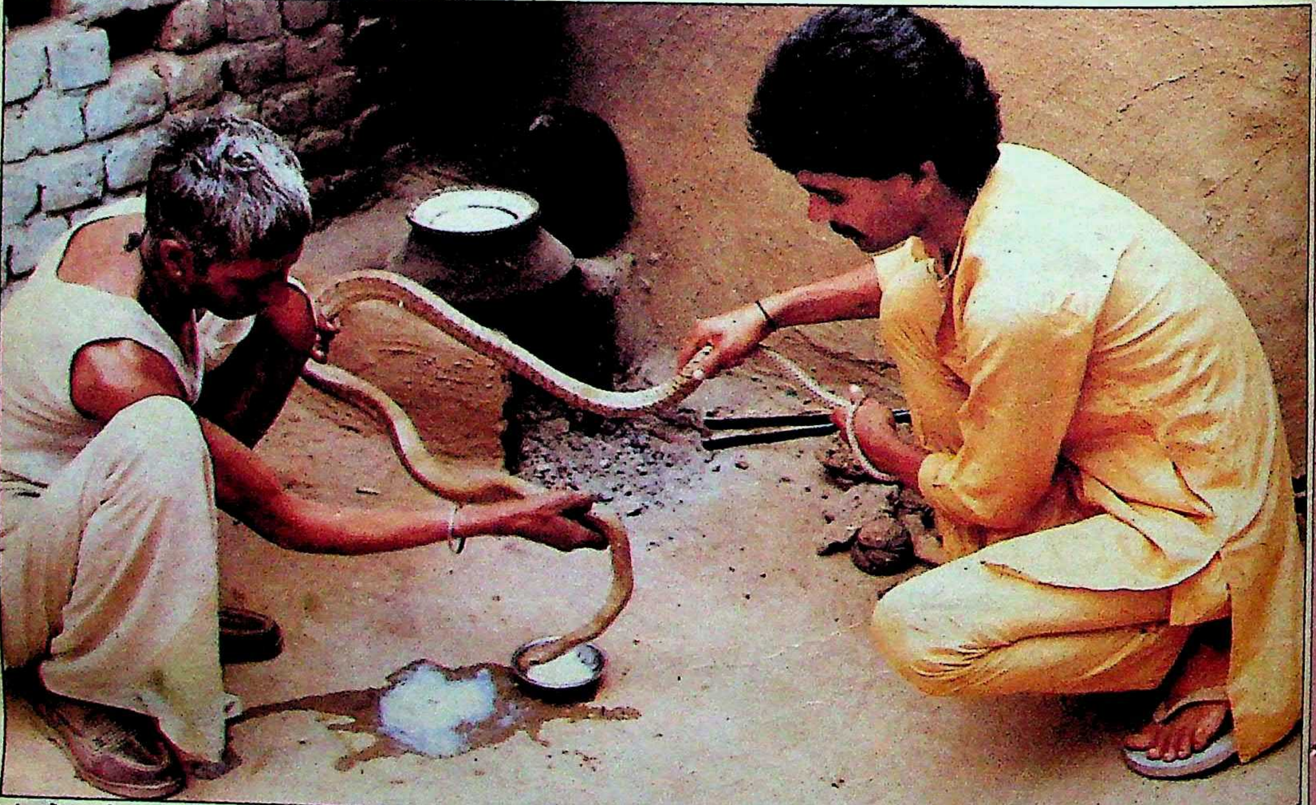

सांप को दूध पिलाना किसी और के लिए घातक होगा, इनके लिए तो नहीं

साधन जब तक नहीं मिलते, तब तक सांपों का साथ छूट भी तो नहीं सकता। सांपों की यह बस्ती दिल्ली से लगभग २५ किमी दूर आगरा-मथुरा रोड पर बसी है। गांव का नाम है मोलड़बंद। संपेरों की यह बस्ती कैसे बनी? यहां के लोग एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं दिल्ली में कोई डेढ़ सौ साल पहले कुछ जमींदार यमुना के कछारों में घूमनेवाले जंगली सूअरों से बड़े आतंकित रहते थे। लाख कोशिशों के बाद भी वे उनसे छुटकारा नहीं पा सके, तो उन्होंने राजस्थान के तीन-चार संपेरों की मदद मांगी। उन संपेरों ने सांपों की मदद से सूअरों का आतंक खतम कर दिया। पुरस्कार के तौर पर जमींदारों ने जमीन आदि देकर उनके बसने का इंतजाम कर दिया। उनका हुनर धीरे-धीरे रंग लाया और राजदरबार में भी उन्हें सम्मान मिलने लगा। कालांतर में तीन-चार परिवार कई परिवारों के रूप में बढ़ गये। और देखते-देखते संपेरों का पूरा गांव आबाद हो गया। अंग्रेजों के समय में भी यह बस्ती आकर्षण का केंद्र रही। सप्ताहांत में अंग्रेज पर्यटक गांव में आते, मनमोहक धुनों पर सांपों का नृत्य देखते और अपना मनोरंजन करते। धीरे-धीरे इस गांव की इतनी ख्याति बढ़ी कि राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व देश के अन्य भागों से आ-आकर संपेरे यहां बसने लगे। अब तो आलम यह कि मोलड़बंद के परिवारों की संख्या ५०० तक पहुंच गयी है।

दर्शकों के लिए सांप भले ही खेल-तमाशे की चीज हों, इन संपेरों के लिए तो वे घर के सदस्य ही हैं। सांपों को वे अपना दोस्त-भाई-बंधु सब कुछ मानते हैं। भयंकर-से-भयंकर विषधर भी उनके घरों में वैसे ही घूमते हैं, जैसे उनके परिजन। ये सांप घर की छतों पर लटककर तरह-तरह के करतब भी करते हैं। गांव के किसी बच्चे या मवेशी को इनसे कोई डर नहीं। वे इनके साथ दोस्तों की तरह खेलते-कूदते हैं। ये सांपों को घुमाने-फिराने के लिए नियमित रूप से बाहर ले जाते हैं।

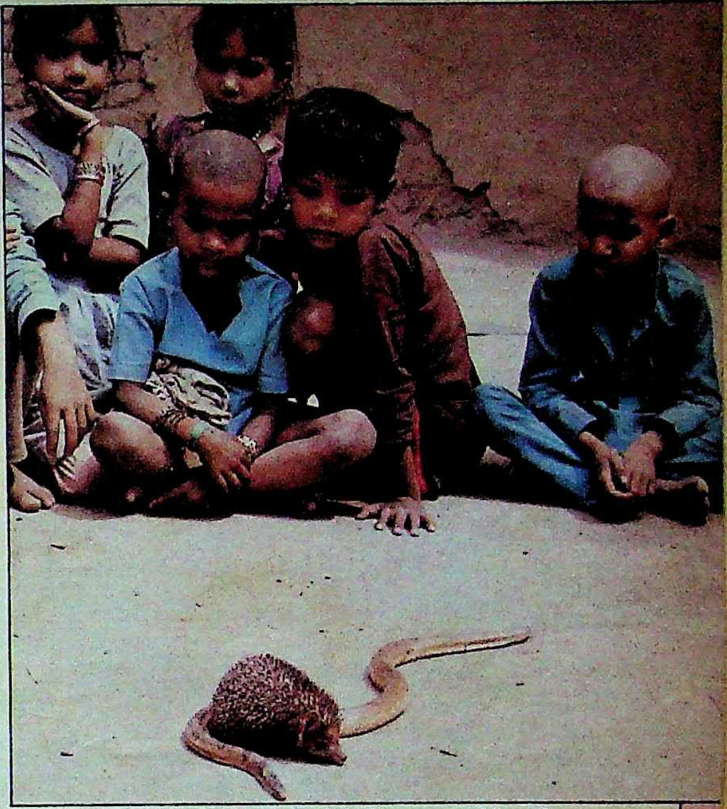

सह अस्तित्व: साही और सांप की अठखेलियों का आनंद लेते बच्चे

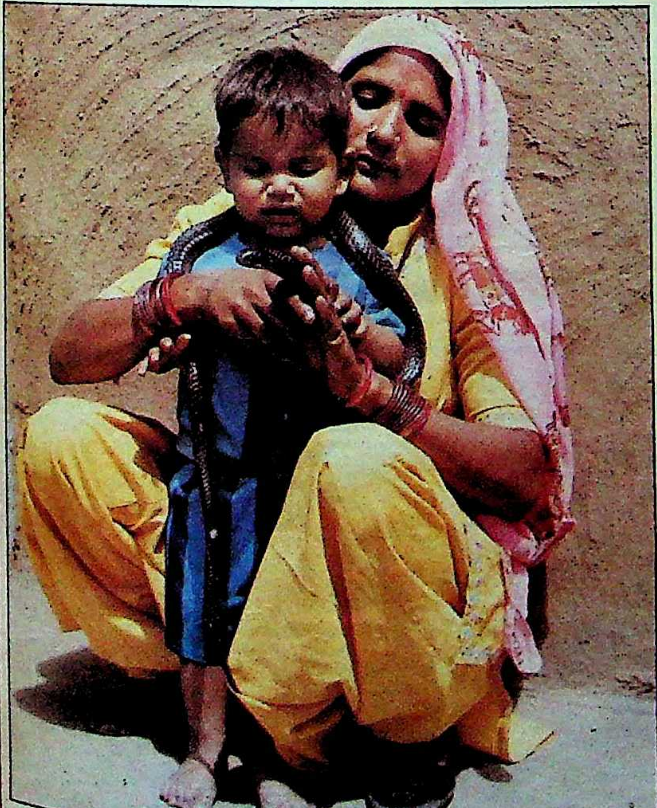

सांप से क्या डर! : एक मां अपने बच्चे की सांप से दोस्ती कराते हुए

कच्चे-पक्के घरों की इस बस्ती में अब पहले जैसा उत्साह देखने को नहीं मिलता। आजकल पहले जैसे संपेरे भी नहीं रहे। आज तो अधिकांश नौसिखिये नौजवान हैं जो केवल बीन बजाकर सांपों के करतब दिखाकर बच्चों का मन बहलाते हैं। एक बुजुर्ग संपेरे का कहना है, "संपेरों में अब पहले जैसी बात नहीं। न हिम्मत है और न इस धंधे में उनका मन लगता है।" आजकल के लड़के अपने पहनावे को छोड़कर पतलूनों पर उतर आये हैं। गांव में बड़े बाल, कानों में छल्ले, गले में बड़े-बड़े मनकों की माला और संपेरों की प्रचलित वेशभूषावाले संपेरे कम ही मिलते हैं। यों भी केवल सांपों के सहारे ये लोग अपनी आजीविका नहीं चला सकते। लेकिन और करने के लिए क्या है! संपेरों के बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर बहुत कम बच्चे ही प्राइमरी से आगे बढ़ पाते हैं।

संपेरों को दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखकर उन्हें कुछ सुविधाएं मुहैया करायी हैं। दसवीं तक शिक्षा प्राप्त किये कुछ संपेरे नवयुवकों को सरकारी कार्यालयों में छोटी-मोटी नौकरियां भी मिली हैं। झोंपड़ियां बनवाने और भैंस खरीदने के लिए भी प्रशासन ने उन्हें पैसे दिये हैं, मगर उनका दर्द है कि सांपों के पुश्तैनी धंधे को सरकार व्यवसाय क्यों नहीं मानती? इस गांव के मुखिया ४० वर्षीय दीनानाथ का कहना है, "हमारे पूर्वज (संपेरे) यह धंधा करते थे। अब भी हम उसी को परंपरानुसार निभा रहे हैं, लेकिन हमारा धंधा पहले जैसा नहीं चल रहा है। सिनेमा-टीवी ने हमें बुरी तरह चोट पहुंचायी है।"

मोलड़बंद गांव में १५-२० किस्म के विषधर सांप हैं जिनमें किंग कोबरा, पद्म नाग, घोड़ा-पछाड़, करैत, काल गणेश, सूरजमुखी, चितल, जलेबी आदि प्रमुख हैं। जलेबी सांप तो जलेबी की तरह घूमता है और आदमी को उछल कर काटता है। संपेरा टेकानाथ का कहना है कि बरसात शुरू होने पर वे जंगलों-खेतों से सांप पकड़ कर लाते हैं। इस काम में महिलाएं नहीं शामिल होतीं। हां घर पर सांपों को

जिनका जहर दवा बनता है: विषधर का विष निकालते हुए

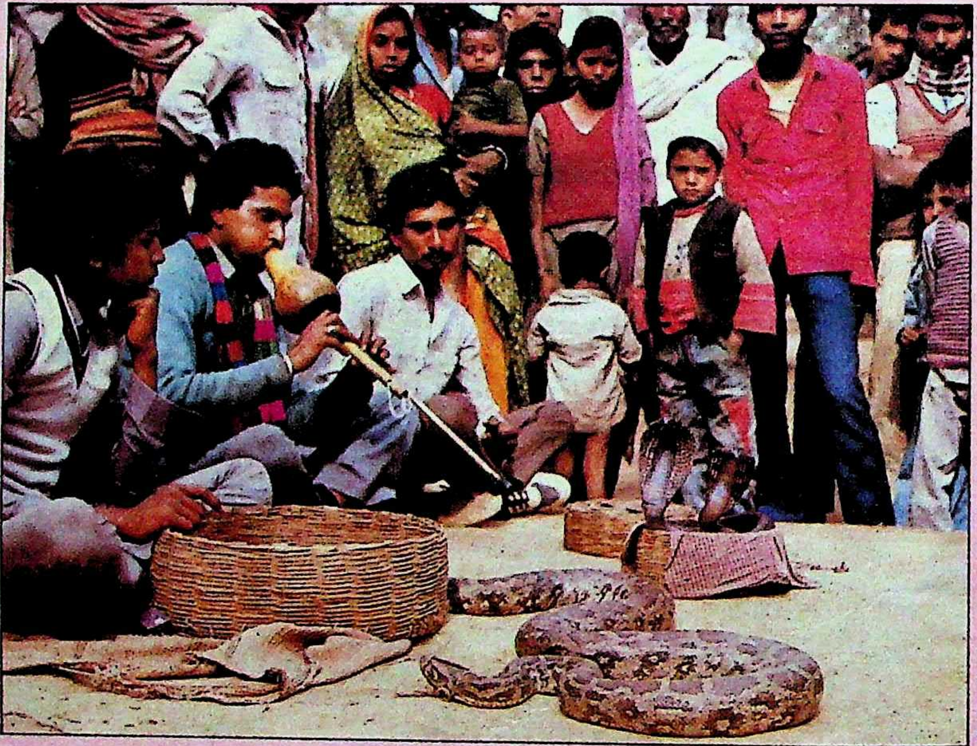

चौपट होता धंधा: सांपों का खेल दिखाता संपेरा

नहलाने, दूध पिलाने या गोश्त खिलाने का काम घर पर वे जरूर करती हैं।

३२ वर्षीय शेषनाथ कहते हैं कि विषधर सांप को वे बड़ी सावधानी से पकड़ते हैं। पर कभी-कभी जब वह काट लेता है, तो अपनी जड़ी-बूटियों द्वारा इलाज भी कर लेते हैं। सांप जिस अंग पर काटता है, उसका खून चाकू से काट कर निकाल दिया जाता है। पर कभी-कभी चाकू से नस भी कट जाती है। वे लोग जो विष निकालते हैं, उसे बंबई की दवा बनाने वाली फैक्ट्री के हाथ बेच देते हैं।

इन संपेरों का धंधा ज्यादातर दिल्ली और हरियाणा के पास के टोले-महल्ले में चलता है। कमाई हुई, तो ४०-५० रुपए मिल जाते हैं, वरना खाली हाथ लौटना पड़ता है। खुद तो भूखे रह जाते हैं, पर सांपों को तो दूध पिलाना ही पड़ता है।

आलेख एवं
छाया: गिरीश श्रीवास्तव

कर्नाटक का नाटक क्या रंग लायेगा ?

कर्नाटक की जनता दल सरकार को बर्खास्त करके शासक दल कांग्रेस ने चुनाव-पूर्व युद्ध का बिगुल बजा अपनी भावी रणनीति और मंशा दोनों को उजागर किया है। प्रश्न यह है कि ऐसा वह किन परिस्थितियों में करने को तत्पर हुई ? केंद्र सरकार का यह कदम कितना न्यायसंगत और लोकतांत्रिक है ? प्रश्न यह भी है कि दलबदल विरोधी कानून को ताक पर रखने की क्या विवशताएं थीं ? इसका राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शुक्रवार २१ अप्रैल को शाम ६ बजे राज्यसभा के जाने-माने जनता पार्टी सांसद डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के लोकसभा दीर्घा में मुदित प्रसन्नचित प्रवेश ने यकायक सबको चौकन्ना कर दिया। चारों ओर नजर दौड़ाते स्वामी की आंखें पत्रकार दीर्घा पर आ टिकीं। बड़बोले स्वामी ने कदाचित पहली बार जबान की जगह इशारे का प्रयोग किया। हाथ गरदन के आर-पार ले जा, उन्होंने कर्नाटक की बोम्मई सरकार की गरदन कलम किये जाने का समाचार आधिकारिक घोषणा के पूर्व ही दे दिया।

इसके पूर्व सप्ताहांत में कर्नाटक सरकार के सर से खतरा टल जाने का माहौल अधिकांश विपक्षी नेताओं की गैरमौजूदगी से स्पष्टतया झलक रहा था। कर्नाटक के राज्यपाल पी. वेंकटसुबैया की बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी की सिफारिश के मुद्दे पर दोपहर तीन बजे राष्ट्रपति से भेंट कर ज्ञापन देने के बाद विपक्ष की निश्चिंतता अस्वाभाविक न थी। वैसे कांग्रेसी खेमे से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछली रात्रि (२० अप्रैल) की काबीना बैठक में अधर में लटकी बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी का निर्णय लिया जा चुका था। किंतु पक्ष-विपक्ष में फैलते विरोध ने राजीव सरकार को इस पर पुन: विचार के लिए बाध्य कर दिया था। जाहिर है, स्वामी के संकेत और औपचारिक घोषणा ने विपक्षी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

आधिकारिक घोषणा स्वामी के सदन में आगमन के दो घंटे बाद लगभग आठ बजे हुई। वह भी सदन के उस दिन के कार्यकाल को तीन किस्तों में बढ़ाये जाने के बाद। जाहिर है कि स्वामी घोषणा के पूर्वनिर्धारित समय की निजी जानकारी के बाद ही लोकसभा में आये थे। जानकार सूत्रों के अनुसार विलंब का कारण औपचारिकताओं की पूर्ति में कमी रही। कदाचित विपक्षी सरकार गिराने के हर्षातिरेक में गृह मंत्रालय लोकसभा की उस नियम-प्रक्रिया को बिसरा बैठा, जिसके तहत गृह मंत्री द्वारा की गयी घोषणा की एक सत्यापित प्रति सदन पटल पर रखना अनिवार्य होता है। गृह मंत्री तत्पश्चात ही उस पर वक्तव्य दे सकते हैं। शाम साढ़े छह बजे जब गृह राज्यमंत्री चिदंबरम ने समस्त कागज गृह मंत्री बूटा सिंह के समक्ष रखे, तो वक्तव्य तो था, किंतु घोषणापत्र नदारद था। नियम-कानून पर नजर और नियंत्रण रखनेवाले लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप ने आपत्ति उठा दी।

कठपुतली : राज्यपाल वेंकटसुबैया

नतीजतन राष्ट्रपति भवन की दौड़ भी शुरू हुई और घोषणापत्र के प्रबंध की प्रक्रिया भी। इसी आपाधापी में सदन के कार्यकाल की तीन किस्तें बढ़ायी गयीं। अंतत: रात आठ बजे विपक्ष के मात्र ४ सदस्यों की मौजूदगी और उनके घोर विरोध और सत्तापक्ष के हर्षोल्लास के माहौल में कर्नाटक सरकार को बर्खास्त और विधानसभा भंग कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर दी गयी। इस प्रकार राज्य में जनता की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर उस पर केंद्र सरकार का कब्जा हो गया।

किसी राज्य में विपक्ष की लोकप्रिय सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करने का यह पहला उदाहरण नहीं है। किंतु कर्नाटक सरकार को जिस ताबड़तोड़ और लोकतांत्रिक तरीके से बर्खास्त किया गया, वह निश्चय ही असाधारण है। विडंबना यह है कि कर्नाटक में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए मात्र केंद्र सरकार ही नहीं, स्वयं दल भी काफी हद तक जिम्मेदार है। राज्यपाल को यह सुअवसर जनता दल के १८ और भाजपा के एक विधायक द्वारा भेजे गये उस पत्र ने प्रदान किया, जिसमें बोम्मई सरकार के समर्थन से हाथ खींचने की सूचना दी गयी थी। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें! गत कुछ महीनों से कर्नाटक सरकार पर गिद्ध दृष्टि लगाये कांग्रेस को बैठे-बिठाये सुनहरा अवसर हाथ लग गया।

स्वामी का आरोप: कर्नाटक सरकार में आवश्यकता से अधिक दिलचस्पी रखनेवाले सुब्रह्मण्यम स्वामी सीधे-सीधे पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को कटघरे में खड़ा करते हैं। 'माया' से उन्होंने कहा, "सारा खेल हेगड़े ने बोम्मई को आतंकित और बाध्य करने के मंशा से रचा था। किंतु उनका यह खतरनाक खेल अंतत: स्वयं उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। कीमत राज्य सरकार को चुकानी पड़ी।" इसकी पुष्टि वे इससे करते हैं कि जिन १८ जनता दल विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेने का पत्र जारी किया, उनमें से अधिकांश हेगड़े खेमे के थे। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि हेगड़े ने विरोध का जो झंडा उठाया, उसका उद्देश्य सरकार को गिराना नहीं, बोम्मई पर दबाव बनाये रखना था। इससे एक ओर वे आरोपों व भंडाफोड़ों से बरी रहना और दूसरे, अपने समर्थकों के लिए समुचित पद मुहैया कर अपने प्रति उनकी वफादारी अक्षुण्ण रखना चाहते थे।

अंतर्कलह का सिलसिला: उल्लेखनीय है कि यह अंतर्विरोध और अंतर्कलह जनता दल में पिछले कुछ महीनों से व्याप्त रहा है। मार्च, १९८५ में कर्नाटक की जनता ने जनता पार्टी को ५ वर्ष शासन करने का जनादेश दिया था। प्रारंभ में राज्य सरकार जनता के विश्वास पर खरी भी उतरती दिखायी दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े की कद-काठी में इतना इजाफा हुआ कि उनकी नजर राज्य की सीमा को पार कर दिल्ली के इर्द-गिर्द केंद्रित होने लगी। अपनी छवि के प्रचार-प्रसार में उनका स्वयं का योगदान कम नहीं बताया जाता। ऐसी स्थिति में केंद्रीय जनता पार्टी नेतृत्व—विशेषकर चंद्रशेखर—के कान खड़े हो जाना लाजिमी था। राष्ट्रीय और राज्य (कर्नाटक) स्तर पर एक-दूसरे को सबक सिखाने का खेल भी यहीं से शुरू हुआ। इसकी परिणति टेलीफोन टेप प्रकरण के भंडाफोड़ और हेगड़े के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से हुई।

हेगड़े अपनी बेइज्जती का कड़ुवा घूंट आसानी से पीनेवाले नहीं थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के मौके पर बदला लेने की

क्या रहस्य है कि हीरो ने अपनी कीमत रखी ऐसी...

हीरो साइकिल विक्रय मूल्य

कीमत

अपनी शुरुआत के बाद, हीरो को अपनी सभी आवश्यक सामग्री में लगातार 16 से 20 गुना बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा है।

यह वास्तव में अविश्वसनीय है कि इस दौरान हीरो साइकिल का मूल्य केवल 4 गुना ही बढ़ा है और आज खरीदार को इतनी कम कीमत पर जो साइकिल मिलती है, वह गुणवत्ता में कहीं अधिक विशिष्ट है। **सम्पूर्ण भारत में एकमात्र हीरो ही अतिरिक्त शक्ति से युक्त साइकिल है क्योंकि इसमें सभी घिसाव वाले कलपुर्जे जैसे — बी बी एक्सल, पैडल एक्सल, हब कोन तथा चेन रोलर कोल्ड फोर्जिंग तकनीक द्वारा निर्मित किए गए हैं।**

इस चमत्कार का राज़ —

हाइ-टैक मशीनें

हीरो अत्याधुनिक हाइ-टैक मशीनों से पूर्णतया युक्त है जिसकी वजह से बिना व्यर्थ किये कच्चे माल के अधिकतम उपयोग द्वारा श्रम कीमत को घटाकर साइकिल मूल्य को प्रतिबन्धित किया जाता है। हीरो के अति व्यावसायिक दल की तकनीकी निपुणता तेल, स्टील व बिजली में ठोस बचत करने में सफल रही है।

उच्च उत्पादन क्षमता

हीरो जैसी उच्च उत्पादन क्षमता वाली कम्पनी में अकर्मण्यता का कोई काम नहीं — न कार्मिकों के लिए, न ही मशीनों के लिए। इसकी उत्पादन क्षमता का मापदण्ड दिये गए समय में कम्पनी को अधिकतम उत्पादन के योग्य बनाता है और कीमतों में नियंत्रण रखता है।

हीरो साइकिल की कीमत में केवल 4 गुना वृद्धि हुई है

यद्यपि वर्ष 1956 में हमारी शुरुआत के बाद स्टील, निकल, पीतल, रबर तथा रंग रोगन में 16 से 20 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि बिजली व मज़दूरी के रेट कई गुना बढ़ गए हैं।

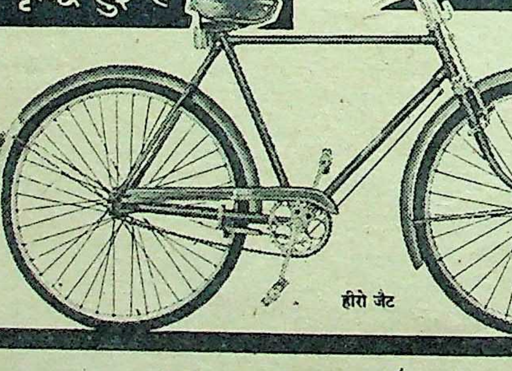
हीरो जैट

हीरो साइकिल्स लिमिटेड
लुधियाना (पंजाब)-साहिबाबाद (उ.प्र.)

हीरो वी आई पी

हीरो स्किपर हाइ-राइजर

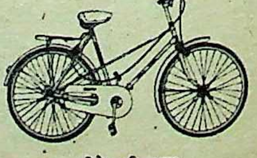
हीरो यूनीबाइक

...जबकि पिछले 30 वर्षों में कीमतों का रुख़ रहा एक तरफा।

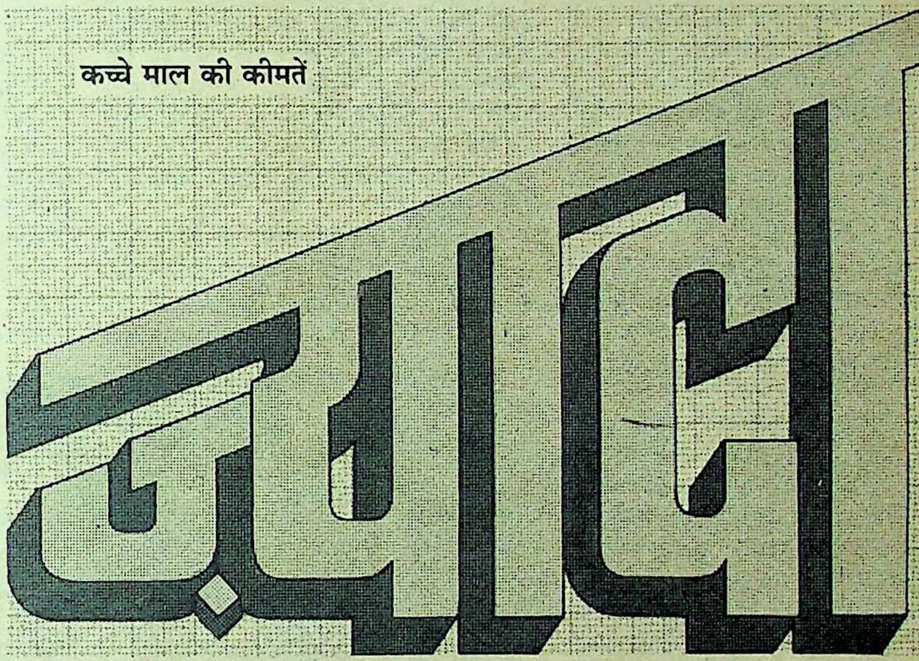

अधिक किफायत के लिए अधिक उत्पादन

ऊपरी व्यय में स्थिरता के कारण ज्यों ज्यों उत्पादन बढ़ता है, उसी अनुपात में प्रति इकाई कीमत कम होती जाती है। प्रतिदिन 10,000 से अधिक साइकिलों के निर्माण के साथ आज हीरो दुनिया भर में सर्वाधिक साइकिलों के निर्माता हैं।

अग्रणी तकनीक

विश्व के शीर्ष निर्माताओं की तकनीक ग्रहण कर अपने अनुकूल बनाने के सिद्धान्त के अन्तर्गत गुणवत्ता और आर्थिक किफायत हेतु हीरो हौंडा के लिए जापान की हौंडा, और मुंजाल शोवा के लिए जापान की शोवा कम्पनियों से किया गया सहयोग वर्तमान तकनीक में निरन्तर विकास लाया है।

सर्वाधिक विस्तृत डीलर नैटवर्क

देशभर में फैला 4000 डीलर्स का जाल एक वर्ष के वारंटी काल में फ्रेम, फोर्क, हैन्डलबार व चेनव्हील की मुफ्त बदल की गारंटी है।

	वर्ष 1956 में कीमत (लगभग)	वर्ष 1989 में कीमत
स्टील	रु. 900 प्रति मी. टन	रु. 14500 प्रति मी. टन
निकल	रु. 22 प्रति कि. ग्राम	रु. 408 प्रति कि. ग्राम
पीतल	रु. 3.75 प्रति कि. ग्राम	रु. 74 प्रति कि. ग्राम
रबर	रु. 1.90 प्रति कि. ग्राम	रु. 22 प्रति कि. ग्राम
इनैमल पेंट	रु. 9 प्रति लीटर	रु. 115 प्रति लीटर
फरनैस ऑयल	रु. 0.25 प्रति लीटर	रु. 4.92 प्रति लीटर
हीरो जैट	**रु. 150**	**रु. 605* केवल**

* स्कूटर टाइप सीट व चेन कवर सहित अधिकतम प्रस्तावित खुदरा मूल्य। फिटिंग चार्जेज़ व स्थानीय कर अतिरिक्त।

HC-NP-208

दुनियाभर में नं० १

HERO BICYCLES

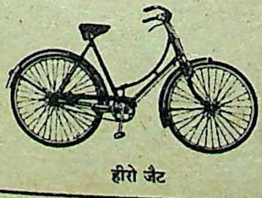
हीरो जैट

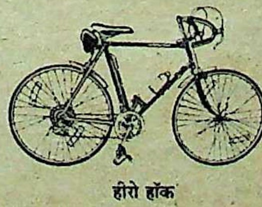
हीरो हॉक

हीरो अपनाएँ — नं० १ होने का अनुभव पाएँ।

निम्नतम मूल्य की क्वालिटी साइकिल

ठानी। यद्यपि अधिकांश लोगों का मानना है कि बोम्मई उनकी पहली पसंद थे, किंतु विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि उनका असली इरादा अपने को पुनः मुख्यमंत्री निर्वाचित कराने का था। ऐसा न होने पर उनकी पहली पसंद बी रचैया थे। बंगलौर में स्थिति के जायजे से स्पष्ट हुआ कि मैदान में एसआर बोम्मई और एच डी देवगौड़ा पहले से ही मौजूद हैं। इस स्थिति में रचैया की उम्मीदवारी से पैदा त्रिकोण में चंद्रशेखर के विश्वासपात्र देवगौड़ा के बाजी मार ले जाने की पूरी संभावना थी। देवगौड़ा को हरहाल बाहर रखने की नीयत से रचैया को मैदान से बाहर कर बोम्मई को समर्थन दे उन्होंने गत अगस्त में मुख्यमंत्री बनवा दिया। मंशा उनका सीधे-सीधे यही रहा कि राज्य सरकार में उनका अप्रत्यक्ष वर्चस्व बना रहे।

प्रारंभ में ऋणी बोम्मई ने हेगड़े को शिरोधार्य कर उनकी मनमर्जी चलने देने का पूरा प्रयास किया। किंतु इससे संतुलन बिगड़ गया और देवगौड़ा नाराज़ हो गये। बात इतनी बढ़ गयी कि १ फरवरी, १९८९ को जनता दल के गठन की औपचारिक घोषणा के समय पार्टी विभाजन के कगार पर पहुंच गयी। साम-दाम-दंड-भेद का सहारा लेकर १११ विधायकों के शपथपत्र प्राप्त कर जनता दल को मान्यता तो दिला दी गयी, किंतु २७ विधायकों को लेकर जब देवगौड़ा मूल जनता पार्टी का बहाना बना अलग हट गये, तो शासक दल के सर पर अल्पमत की नंगी तलवार लटक गयी। दलदल में फंसी बोम्मई सरकार की हलाली के लिए कांग्रेस माकूल मौके की तलाश में जुट गयी। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने इस मकसद से कर्नाटक की कई यात्राएं कीं।

मौके की तलाश में राज्यपाल वेंकटसुबैया भी थे। जनता दल सरकार को जिस प्रकार बिना किसी परेशानी के उन्होंने मान्यता दे दी थी, उससे कांग्रेस आलाकमान उनसे बेहद नाराज था। जनता सांसद जयपाल रेड्डी के अनुसार राज्यपाल को दिल्ली बुला कर इतनी खिंचाई की गयी कि उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया था। इस्तीफा तो बिना मंजूरी रोक लिया गया, किन्तु उनको इस आवश्यक निर्देश के साथ बंगलौर रवाना किया गया कि वे येन-केन प्रकारेण बोम्मई सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन की जमीन तैयार करें और इस तरह अपनी योग्यता और वफादारी का परिचय दें। कदाचित इसीलिए जब मौका उन्हें हाथ लगा, तो उन्होंने संवैधानिक नियम-प्रक्रिया और वैध-अवैध के प्रश्न को भी पूर्णतया नजरअंदाज कर दिया।

तात्कालिक कारण: जनता दल में बगावत का फौरी कारण गत १५ अप्रैल को बोम्मई मंत्रिमंडल का पुनर्विस्तार रहा। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री बोम्मई कुछ दिनों से हेगड़े की गिरफ्त से आजाद होने और अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में थे। इसी के चलते उन्होंने पार्टी के विभिन्न धड़ों से वायदे भी कर लिये और सत्तासुख की उनकी लालसा भी बढ़ा दी, किंतु विभिन्न धड़ों में संतुलन बनाये रखने के लिए जिस योग्यता की जरूरत थी, उसकी उनमें कमी थी। पार्टी को एकजुट और अनुशासित करने का कोई प्रयास नही हुआ। नतीजतन चौतरफा अव्यवस्था, आपाधापी और गुटबंदी का बाज़ार गर्म हुआ।

अपनी सरकार को गिराने के काम में नये-पुराने विधायक 'ओवर टाइम' काम करने लग गये। इनमें हेगड़े के वे दोस्त थे—मसलन जीवराज अल्वा—जिन्हें बोम्मई मंत्रिमंडल के एयर बस जैसे विस्तार के बाद भी जगह नहीं मिल पायी थी। दूसरी तरफ देवगौड़ा के वे मित्र थे, जिन्होंने जनता दल में शामिल होने का शपथपत्र तो भर दिया था, लेकिन जो बोम्मई को हेगड़े का प्रतिनिधि मान उन्हें हटाना चाहते थे।

दिलचस्प बात यह है कि बोम्मई ने एक महीने पहले गत १३ मार्च को अपने मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया, तो उन्होंने इसे चुनाव वर्ष का 'युद्ध मंत्रिमंडल' कहा था। एक ही महीने बाद जब उन्होंने उसमें १३ मंत्री और जोड़े, तो उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।

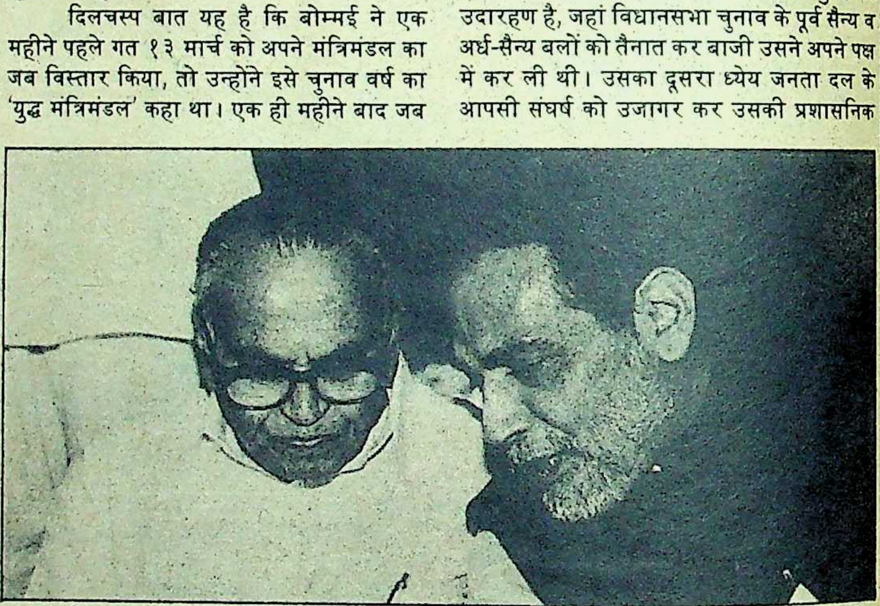

संतुलन बिगड़ गया: बोम्मई और रामकृष्ण हेगड़े

संकट में फसने का यह पहला मौका नहीं था। गत मार्च में वित्त विधेयक पर विधानसभा में मतदान के समय उनकी सरकार अपने ही विधायकों की लापरवाह गैरमौजूदगी के कारण संकटग्रस्त होकर बाल-बाल बची थी। ऐसे में ७ निर्दलियों, ६ कम्युनिस्टों और २ भाजपा विधायकों के समर्थन से २२२ सदस्यों वाली विधानसभा में १११ विधायकों वाली अल्पमत बोम्मई सरकार के पास चौकस रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह चौकस नहीं रही इसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ा। मंत्रिमंडल से बाहर छूट गये असंतुष्ट विधायकों को यदि हेगड़े समर्थकों—जीवराज अल्वा और इनामदार तथा देवगौड़ा के खासमखास कल्याणराव भोलाकेरी—ने फोड़ लिया, तो आश्चर्य नहीं। विशेषकर इसलिए, क्योंकि इस शुभ काम को पूरा करने के लिए कांग्रेस प्रोत्साहनस्वरूप खुले हाथ से धन बांट रही थी। जनता दल नेताओं का दावा है कि प्रति विधायक ४० से ५० लाख रुपए तक खर्च करने में कांग्रेस ने कोताही नहीं बरती। दूसरी ओर बूटा सिंह का कहना है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल के विधायकों की कीमत पिछले दस साल में दस गुना बढ़ी है। उनका कहना है कि १९८८ में राज्यसभा चुनाव के समय एक विधायक की कीमत दो लाख थी, तो विधानसभा भंग होने से पहले बीस लाख तक पहुंच गयी।

कांग्रेस की रणनीति: कांग्रेस की नीयत और रणनीति थी—बोम्मई सरकार को गिरा कर जनता दल को लोकसभा चुनाव से पूर्व सुख, लाभ, व सुविधा से वंचित कर अपने लिए फायदे का एक और दरवाजा खोलना। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में कांग्रेस के सामने मार्क्सवादी शासन वाले राज्य त्रिपुरा का उदारहण है, जहां विधानसभा चुनाव के पूर्व सैन्य व अर्ध-सैन्य बलों को तैनात कर बाजी उसने अपने पक्ष में कर ली थी। उसका दूसरा ध्येय जनता दल के आपसी संघर्ष को उजागर कर उसकी प्रशासनिक क्षमता, टिकाऊपन और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाना था। मुहिम का प्रमुख लक्ष्य कर्नाटक में पार्टी को सत्तारूढ़ करने की अपेक्षा आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों को पक्का करना अधिक है। रणनीति ठीक श्रीमती गांधी जैसी है—उत्तर भारत की संभावित क्षति को दक्षिण भारत से पूरा करना।

इसी को अमली जामा पहनाने में राज्यपाल पी वेंकटसुब्बैया ने भरपूर सहायता की। बागी विधायकों का पत्र मिलने के बाद मुख्यमंत्री से इसकी चर्चा करने की औपचारिक कार्रवाई के बजाय उन्होंने सीधे-सीधे बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी की अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजना अधिक उचित समझा। अपने घर पर वीडियो में पुरानी हिंदी फिल्म 'जंजीर' देखने में व्यस्त-आश्वस्त मुख्यमंत्री को जब तक इस षड्यंत्र और उसकी गंभीरता का अहसास हुआ, तब तक पानी सर से ऊपर निकल चुका था। फलस्वरूप उनका २७ अप्रैल को विधानसभा अधिवेशन बुला अपना बहुमत सिद्ध

करने का ऐलान, साथ ही असंतुष्ट विधायकों को मनाने की योजना तब विफल सिद्ध हुई, जब राज्यपाल ने उनकी एक न सुनी—बावजूद इसके कि १८ में से १२ विधायकों ने राज्यपाल को दुबारा पत्र लिखकर सूचित किया था कि वे बोम्मई सरकार को पुनः समर्थन दे रहे और अपना पहले का पत्र वापस ले रहे हैं। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजे गये अपने दूसरे संदेश में भी—जिसमें कुछ बागी विधायकों के पुन: बोम्मई सरकार को समर्थन देने का हवाला था—बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी की अपनी सिफारिश बरकरार रखी। दलील कर्नाटक विधायकों के खरीद-फरोख्त की मंडी बन जाने की दी गयी।

भाकपा के वरिष्ठ सांसद इंद्रजीत गुप्त के अनुसार बहुमत सिद्ध करने का स्थान राजभवन नहीं सदन है। यदि राज्यपाल २७ अप्रैल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अवसर दे देते, तो कोई आसमान सर पर नहीं फट पड़ता। प्रश्न यह उठता है कि राज्यपाल ने ऐसा क्यों नहीं किया? जवाब में कर्नाटक के जनता दल के वरिष्ठ सांसद एमएस गुरुपदस्वामी ने 'माया' से कहा, ''मुख्य कारण वह राजनीतिक निर्णय था, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिया था। विपक्षी सरकारों को गिराना आज कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम का सर्वप्रथम मुद्दा है। राजीव गांधी द्वारा संचालित इस योजना में जल्लाद की भूमिका बूटा सिंह ने निभायी।''

असंतुष्टों का नेतृत्व: देवगौड़ा

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बोम्मई सरकार गिराने के प्रश्न को लेकर कांग्रेस स्पष्टतया दो खेमों में विभाजित हो गयी थी। कुछ वरिष्ठ नेताओं, जैसे नरसिम्हाराव, वीरेंद्र पाटिल, आस्कर फर्नांडीस आदि ने इस समय और इस प्रकार बोम्मई सरकार गिराने से असहमति प्रकट करते हुए कहा था कि इससे सहानुभूति लहर जनता दल के पक्ष में हो जायेगी। उनका मानना था कि २७ अप्रैल को विधानसभा में बोम्मई अपना बहुमत साबित नहीं कर पायेंगे। उनकी सरकार खुद-ब-खुद गिर जायेगी। किंतु इनकी बात न मानी गयी। कारण अधिकांश नेताओं की राय यही रही कि इस दौरान मुख्यमंत्री बोम्मई खरीद-फरोख्त करके न केवल अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे, बल्कि इसके बाद अगले छह महीने—अर्थात आम चुनाव तक—विधानसभा का अधिवेशन बुलायेंगे ही नहीं। कांग्रेसियों के अनुसार बोम्मई द्वारा बागी विधायकों को भरपूर सत्ता-सुख देने के वायदे के अलावा फी विधायक २० लाख रुपए तक भेंट किये गये। यह रकम भेंट की गयी या नहीं, यह कहना कठिन है। लेकिन यह सच है कि यदि विधानसभा का २७ अप्रैल को अधिवेशन होता, तो समर्थन न देनेवाले जनता दल विधायक दल विरोधी कानून की चपेट में आ जाते और सरकार हर हाल सुरक्षित रह जाती। बोम्मई की इस चाल की काट के लिए कांग्रेस ने फौरी कार्रवाई करना और मौके का लाभ उठाना ही उचित समझा।

कांग्रेस मौके का लाभ उठाने की बात से इनकार करती है। उसके अनुसार कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक संवैधानिक और जनहित की कार्रवाई थी। बलिराम भगत ने कहा कि १९७७ में जनता सरकार ने तो नौ राज्यों की कांग्रेस सरकारों को सत्तारूढ होते ही चटपट बर्खास्त कर दिया था। स्वयं कर्नाटक में तत्कालीन राज्यपाल गोविंद नारायण ने देवराज अर्स की सरकार को बर्खास्त करने में कोताही नहीं की थी। कर्नाटक में १९७७ में खुद दलबदल के भुक्तभोगी पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल ने कहा कि जनता दल की सरकार भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अव्यवस्था, आपसी कलह और पदलोलुपता की वजह से गिरी है। इसे गिराने में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रही। एक अन्य कांग्रेसी सांसद मखौल करते बोले, ''जनता दल को आज सबसे बड़ी शिकायत है कि जब उन्होंने अपने ही घर में आग लगायी, तो कांग्रेस ने फायर ब्रिगेड—और वह भी पहले से—बुलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की?''

इशारा हेगड़े की ओर: सुब्रह्मण्यम स्वामी

आरोपों-प्रत्यारोपों की बाढ़ के बीच मुख्य प्रश्न लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रिया का है। इसमें राई-रत्ती संदेह नहीं कि राज्यपाल के पद का दिनोदिन राजनीतिकरण होता जा रहा है। असम गण परिषद के सांसद दिनेश गोस्वामी के अनुसार अधिकांश राज्यपाल कांग्रेस के 'रिजेक्ट' राजनीतिज्ञ हैं। जिन्हें कहीं और ठौर नहीं मिलता, उन्हें इस पद पर बिठा दिया जाता है। गत एक-डेढ़ दशक में यह भावना प्रबल हुई है कि राज्यपाल केंद्र सरकार का हितरक्षक है। केंद्र में सत्तारूढ़ कोई सरकार यदि यह समझे कि 'जिसका राज्यपाल उसका राज' तो कदाचित सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र के विकास के लिए यह अत्यधिक घातक सिद्ध होगा।

राज्यपाल वेंकटसुब्बैया ने १९ विधायकों के हस्ताक्षरयुक्त एक अकेले पत्र के सहारे बोम्मई सरकार को बर्खास्त करने की जो कार्रवाई की है, वह संविधान की दसवीं अनुसूची—जो दलबदल विरोधी कानून को कारगर और सुदृढ़ बनाती है—का न केवल हनन करती है, बल्कि सरकारिया आयोग की इस सिफारिश की भी अवहेलना करती है कि बहुमत का निर्णय सदन में होना चाहिए। जयपाल रेड्डी ने सवाल उठाते हुए 'माया' से कहा कि अगले चुनाव में यदि कांग्रेस को लोकसभा की मात्र पौने तीन सौ सीटें मिलें, तो क्या उसके ३० असंतुष्ट सांसदों द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखे जाने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर देंगे?

कर्नाटक प्रकरण को लेकर जो स्थिति आज दरपेश है, उसके निस्संदेह दूरगामी परिणाम होंगे। इस मुद्दे पर पुन: एकजुट हुए विपक्ष को जनता की अदालत में जाने से राजनीतिक लाभ मिलेगा, ऐसा पर्यवेक्षकों का मानना है। कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव शीघ्र करा लोकतंत्र की बहाली की मांग की है। किंतु आम चुनाव (लोकसभा) के पूर्व इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष को सत्ता-सुख से वंचित रख अधिकाधिक सुख-लाभ अपने लिए सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन अरुण नेहरू इसे कांग्रेस का दिवा-स्वप्न मानते हैं। उन्होंने 'माया' से कहा, ''तमिलनाडु में जानकी समचंद्रन की सरकार गिरा कर महीनों राष्ट्रपति शासन लागू करने और स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राज्य का १३ बार दौरा करने के बावजूद वहां हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें मात्र २५ सीटें हाथ लगीं। कर्नाटक ही नहीं, समूचे देश में कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी कदमों का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी।''

जनता दल के अनुसार बोम्मई सरकार की, क्षति राष्ट्रीय लाभ में बदल जायेगी। यही नहीं विपक्ष के लिए भी यह सबक है कि आपसी कलह और फूट अंततः आत्मघाती सिद्ध होती है, विशेषकर इसलिए कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदे में रहता है।

—रंजना कक्कड़

त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव के साथ

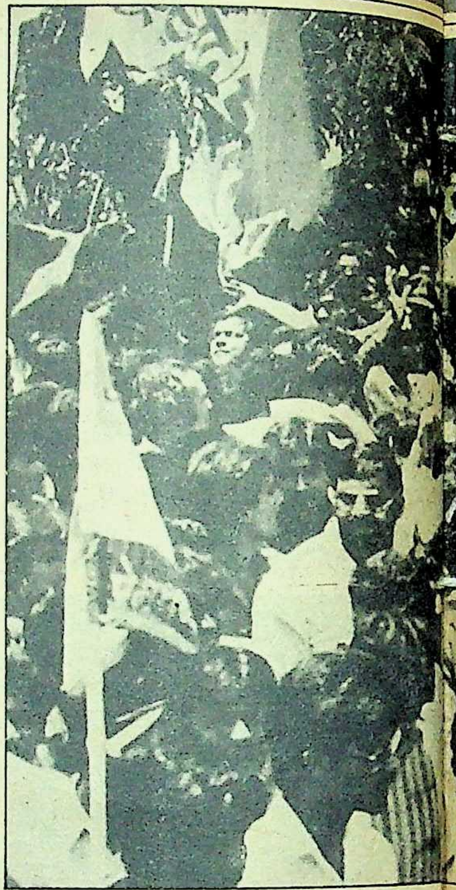

अर्जुन सिंह का जेहाद

मध्य प्रदेश में दौरों की अपनी राजनीति है। जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो वोरा-सिंधिया की जोड़ी के दौरे काफी चर्चित-विवादास्पद थे। अब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री हैं, तो अर्जुन सिंह के दौरे चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये दौरे अर्जुन सिंह ने चुरहट लाटरी संबंधी मामले में सर्वोच्च न्यायालयके फैसले के बाद बड़ी धूमधाम से शुरू किये हैं। बताया जाता है कि अर्जुन सिंह ने स्वयं राजीव गांधी से इन दौरों की अनुमति यह कहकर ली है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दो टूक न होने के कारण भाजपा नाजायज फायदा उठा सकती है, इसलिए उन्हें व्यापक दौरे करके जनता को यह समझाना होगा कि सर्वोच्च न्यायालयका फैसला उनके हक में है। लेकिन सिंह के विरोधियों का कहना है कि अर्जुन सिंह के दौरों का असली उद्देश्य वोरा की नींद हराम करना और अपना जनाधार प्रदर्शित करना है। दौरे शुरू करने के लिए भोपाल-आगमन पर अर्जुन सिंह का जैसा स्वागत सत्कार हुआ है, उसे किस रूप में देखा जा रहा है और आगे चलकर सिंह का यह 'जेहाद'. क्या रंग लेनेवाला है ?

२४ अप्रैल, १९८९, समय : दोपहर एक बजे, जगह भोपाल हवाई अड्डे के बाहर एक क्रुद्ध उत्सव।

वक्ता : अर्जुन सिंह, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

भाषण : "ग्वालियर से लेकर बस्तर तक किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वह श्री राजीव गांधी को अपने कंधों पर ढोकर चल रहा है। राजीवजी हैं, तो हम आप हैं और अपनी इस सीमा को जो नहीं समझेगा उसे पार्टी और जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।...

*"**हमारी लड़ाई** उन सामंती तत्वों और राजा-रानियों से है, जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा चोट मारी है। इस लड़ाई में जो कांग्रेसी सामंतवाद का साथ देंगे, वे इतिहास के काले पन्नों में समा जायेंगे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद से कांग्रेस को डिगाना चाहते हैं, उन्हें हम पहचानते हैं और उनसे सड़क पर निपट लेंगे।"*

अर्जुन सिह के राजनीतिक उग्रवाद का यह पहला कदम था और इस पहले कदमं की राजनीतिक आहटें काफी जोरदार हैं। संकेतों और भंगिमाओं में बात करनेवाले अर्जुन सिह जब 'ग्वालियर' और 'बस्तर' बोलते हैं, तो किसी को संदेह नहीं रहता कि वे रेल राज्यमंत्री माधवराव सिंधिया और मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बारे में कह रहे हैं। इस पार या उस पार का जवाबी हमला शुरू हो गया है।

२४ अप्रैल को सिह की विजय-यात्रा जब हवाई अड्डे से भोपाल शहर की ओर बढ़ रही थी, विधानसभा में कांग्रेस-इ की खाली बेंचों को देख कर सबसे ज्यादा चुहलभरी चिंता भारतीय जनता पार्टी नेता कैलाश जोशी को हो रही थी। आमतौर पर सादगी की सीमा तक गंभीर रहनेवाले जोशी ने वोरा से पूछा, "मुख्यमंत्री जी , आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है ? क्या अर्जुन सिह हवाई अड्डे से सीधे राजभवन जाकर शपथ ग्रहण करेंगे ?"

वोरा ने कहा, "यह हमारी पार्टी का अपना मामला है। कम-से-कम अभी आप तो शपथ ग्रहण करने नहीं जा रहे हैं।"

कैलाश जोशी ने नहले पर दहला जड़ा, "लेकिन आपके सारे विधायक हवाई अड्डे गये हुए हैं और विधानसभा में आपकी तरफ से बोलनेवाले बहुत कम बचे हैं। हमारी चिंता तो यह है।"

लेकिन अगले दिन 'माया' से बातचीत में वोरा की चिंता 'यह' नहीं लग रही थी। काफी दयनीय आक्रामकता से भरे, विधानसभा के अपने बड़े और सूने कक्ष में बैठे वोरा ने कहा, "अर्जुन सिहजी हमारी पार्टी के नेता हैं और उनका स्वागत अगर होता है, तो यह उनके साथ ही पार्टी की लोकप्रियता का भी सबूत है।"

लेकिन वोरा ने बार-बार कहने और लगभग उकसाने पर भी यह कहने की उदारता नहीं दिखायी कि अगर यह पार्टी की लोकप्रियता का प्रदर्शन था, तो वे खुद भी उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। उन्होंने अलबत्ता यह जरूर कहा कि मैं तो सिह का मित्र हूं और उत्सव में जाने, न जाने से मेरी मित्रता में कोई बाधा नहीं पड़ती। लेकिन इसी राजनीतिक मित्रता में वोरा और सिंधिया समर्थक युवक कांग्रेस द्वारा विजय-यात्रा में अवरोध और जवाबी खूनखराबा कहां से आया, इसका कोई जवाब वे नहीं देते। वे कांग्रेस-निष्ठा की परिचित और रटी हुई भाषा में बोलने लगते हैं।

असंतुष्ट की भूमिका में अर्जुन सिह को देखना मध्य प्रदेश के लिए थोड़ा अजनबी अनुभव है। लेकिन जैसाकि सिह खुद स्वीकार करते हैं कि वे उन लोगों में से हैं, जिन्होंने 'असंतुष्ट' शब्द का भारतीय राजनीति में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उस समय वे मध्य प्रदेश के मंडलोई मंत्रिमंडल की शिकायत लेकर पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिलने आये थे और दिल्ली में जब पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस में उनकी हैसियत पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं

वोरा की नयी मुसीबत: भोपाल में अर्जुन सिंह का स्वागत जुलूस

"ग्वालियर संभाग के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाममात्र का भी आधार नहीं है, लेकिन हमारी अपनी गलती से ही उन्हें आधार का भ्रम फैलाने का मौका मिल रहा है। अगर यह धारणा बन रही है कि कांग्रेस में भविष्य तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया गया है, तो यह मुख्यमंत्री का काम है कि इसे गलत साबित करें। मैं इसी काम में उनकी मदद करना चाहता हूं," सिंह एक चतुर रहस्यमय हंसी से भर कर कहते हैं।

विद्रोही नहीं 'असंतुष्ट' हूं। अर्जुन सिंह बताते हैं कि उस समय कांग्रेसी होने की इस नयी परिभाषा को अखबारों—खासतौर पर 'स्टेट्समैन' ने काफी मजेदार रहस्योद्घाटन की मुद्रा में छापा था। यह बात और है कि बाद में यह शब्द कांग्रेस से सत्ताविमुख खेमे का प्रतीक बन गया और अपनी रची हुई परिभाषा का सामना सिंह को भी काफी करना पड़ा।

लेकिन सिंह इस बार एक समर्थ नेता की नाराज मुद्रा में हैं। भोपाल में इस नाराजगी को सार्वजनिक करने के पहले दिन ही उन्होंने अपने भविष्य की पगडंडियां तय कर दीं और उनके खास समर्थक सांसद अजीत जोगी जब यह कहते हैं कि 'आखिरकार पगडंडियां ही राजमार्ग तक जाती हैं, तो जाने-अनजाने ही वे अपनी रणनीति की घोषणा कर रहे होते हैं।

भोपाल में पहले शक्ति-प्रदर्शन में सिंह ने अपने विरोधियों के हथियार को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का रास्ता चुना। उन्होंने प्रकटत: तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमला बोला, लेकिन उसमें नाम, मुकदमा करनेवाले कैलाश जोशी के बजाय पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजया राजे सिंधिया का लिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को 'सत्य की जीत' मानते हुए, सारे हंगामे को उसी जीत का उत्सव माना गया था, लेकिन अपनी इस जीत को भी सिंह निरापद नहीं बता सकते। उन्हें लगातार सभाओं और वक्तव्यों में इस कानूनी फैसले का शाब्दिक नहीं, मार्मिक अर्थ बताना पड़ रहा है और उनके करीबी विधायकों में से मुकेश नायक, रमाशंकर सिंह और मंत्रियों में से बीआर यादव की अपेक्षा यही है कि न्यायालय को अपना मंशा और स्पष्ट कर देना चाहिए था। इसी मुद्दे को प्रतिपक्ष के नेता कैलाश जोशी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना बताते हुए खुद अपील करने जा रहे हैं कि न्यायालय अपना मंतव्य स्पष्ट करे।

जोशी खुद के रचे इस अग्निकांड को बहुत ही निस्पृह उत्सुकता से देखते हैं, "न्यायालय का मंतव्य स्पष्ट है कि वह भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन फैसले की राजनीतिक व्याख्या चूंकि की जा रही है, इसलिए मैं खुद उच्चतम न्यायालय से अनुरोध कर रहा हूं कि वह अपने फैसले को और साफ शब्दों में व्यक्त करे ताकि अनपढ़ होने का स्वांग कर रहे लोग भी इसे समझ सकें," हंगामे-भरी विधानसभा की लाबी में बैठे जोशी ने कहा।

काफी दिलचस्प संयोग से जोशी और वोरा फैसले के बारे में एक ही भाषा में बोलते हैं और वह भाषा कृतज्ञता की है। वोरा कहते हैं, "हमने तो हाईकोर्ट के फैसले को भी माना था और हम सुप्रीमकोर्ट के फैसले को भी मानेंगे। लेकिन कांग्रेस की अपनी एक और सुप्रीम सत्ता है और वह है, राजीव गांधी।"

भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी भी लगभग यही बात कहते हैं, लेकिन स्वाभाविक राजनीतिक कारणों से उनकी सुप्रीम सत्ता राजीव गांधी नहीं हैं। उनका कहना है, "फैसला जनता की अदालत में होगा। किराये की भीड़ या जबरन की गयी व्याख्याएं किसी की कुरसी नहीं बचा सकतीं।"

प्रसंगवश जोशी, सिंह की कैरवा बांधवाली कोठी—जिसे वे महल कहते हैं— को खरीदने के लिए उत्सुक हैं। "मैं चंदा करके पैसा जमा करूंगा और फिर कैरवा महल खरीद कर उसे संत-निवास बना दूंगा," वे कहते हैं और इसका कारण बताते हैं कि संतों का पुण्य भ्रष्टाचार से बने महल को पवित्र कर देगा। पवित्र होने के बाद वे इस महल का क्या करेंगे—यह अभी उन्होंने तय नहीं किया है।

भोपाल से १५ किलोमीटर दूर एक बांध के सिर पर धुंधले सपने की तरह खड़ा सिंह का यह घर 'देवश्री' सलीके, सुरुचि और समृद्धि से मिलकर बना है और इसके भीतर जाकर लगता है कि इसके बनने के पीछे के आरोपों के पीछे इसके भीतर न रह पाने की जलन भी एक कारण हो सकती है। फर्श संगमरमर के हैं जो कैलाश जोशी के अनुसार करोड़ों

ग्लूकॉन-डी सुपरहीरो.

चुस्ती-फुर्ती से लबालब,
थका देनेवाली
गर्मी में भी.
Glucon-D
200g
High grade, finely powdered glucose enriched with vitamin D and calcium phosphates
200 GRAMS NET
GLINDIA LIMITED
Dr. Annie Besant Road
Bombay 400 025, India.
Max. Price
Rs.
Local Taxes
Extra
® Owner of the Registered Trade Mark
असली,
रंगारंग पैक
देख कर
लीजिए.

थका देनेवाली गर्मी के दिन में आपके बच्चे को चाहिए ग्लूकॉन-डी: ग्लूकोज़, विटामिन-डी और कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट से भरपूर तुरंत शक्ति देनेवाला पेय.

फलों के रस, दूध, चाय, कॉफी या पानी में मिला कर पीजिए-पिलाइए ग्लूकॉन-डी. पूरे परिवार के लिए ताज़गीदायक पेय. 100, 200, 500 ग्राम पैक में उपलब्ध.

ग्लूकॉन-डी

शक्ति देनेवाला पेय. सुपरहीरो की खास पसंद.

HTA 1649

जुझारू तेवर: अर्जुन सिंह का शक्ति प्रदर्शन

अब शक्ति-प्रदर्शन से जो अभियान आरंभ हुआ है, उसकी परिणति प्रदेश भर की यात्रा में होगी। यह एक तरह से कांग्रेस के चुनाव-अभियान की स्वयंभू और अघोषित शुरुआत है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सिंह ने क्या इसके लिए राजीव गांधी से पूछ लिया है?

के हैं और सिंह परिवार के अनुसार एक मित्र व्यापारी की मदद से उन्हें बहुत सस्ता मिल गया था। अतीत के वैभव को समकालीन करते हुए भव्य सोफे हैं और इन्हीं में से एक पर एक तरफ अपने चित्रों से भरे अखबारों और दूसरी ओर प्राचीन शैली के एक टेलीफोन के बीच बैठे सिंह अपनी रणनीति के बारे में बात करते हैं, विस्तार से और आसानी से। यह बात और है कि वे इसे रणनीति कहने से इनकार कर देते हैं और महज राजनीति मानते हैं।

हवाई अड्डे के अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि वे वोरा के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। क्या इसका अर्थ यह लगाया जाये कि वोरा के हाथ मजबूत नहीं हैं या वे सिंह की मदद के बिना शासन नहीं कर सकते?

सिंह कहते हैं कि यह वोरा के व्यक्तिरूप की नहीं, पार्टी के एक प्रतिनिधि की बात है। "उसे और अधिक मजबूत होना चाहिए और हर कांग्रेसी को उसके मजबूत होने में मदद करनी चाहिए। ग्वालियर संभाग के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाममात्र का भी आधार नहीं है, लेकिन हमारी अपनी गलती से ही उन्हें आधार का भ्रम फैलाने का मौका मिल रहा है। अगर यह धारणा बन रही है कि कांग्रेस में भविष्य तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया गया है, तो यह मुख्यमंत्री का काम है कि इसे गलत साबित करें। मैं इसी काम में उनकी मदद करना चाहता हूं, सिंह एक चतुर रहस्यमय हंसी से भर कर कहते हैं।

लेकिन फिर वे वोरा को निकम्मा मानते अगर आज उनके समर्थक वोरा को निकम्मा मानते हैं, तो उन्हें इस पद पर लाकर खुद सिंह ने क्या गलती नहीं की? "उस समय वोरा का चुनाव एकदम प्राकृतिक था। उनसे वरिष्ठ सारे नेता संसद में चुने गये थे और वे खुद भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। मुझे नहीं लगता कि वोरा को चुनवाकर मैंने कोई गलती की," सिंह स्पष्ट करते हैं और बहुत साफ चुप्पी से इस सवाल को टाल जाते हैं कि चुनते समय नहीं पर क्या बाद में भी, उन्हें नहीं लगा कि वोरा गलत चुनाव साबित हुए हैं?

भोपाल में २४ अप्रैल को जो हुआ, वह तीन महीने में अर्जुन सिंह खेमे का दूसरा शक्ति-प्रदर्शन था। पहली बार ४ दिन तक विधायक दल के नेता का चुनाव स्थगित करवाने और देशभर में राजनीतिक अस्थिरता की सनसनी फैलाने के बाद सिंह के ही हस्तक्षेप के बाद वोरा को स्वीकार किया गया। वोरा उन्हें शायद कम खतरनाक और अधिक निरापद विकल्प लगे होंगे।

अब शक्ति-प्रदर्शन से जो अभियान आरंभ हुआ है, उसकी परिणति प्रदेश भर की यात्रा में होगी। यह एक तरह से कांग्रेस के चुनाव-अभियान की स्वयंभू और अघोषित शुरुआत है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सिंह ने क्या इसके लिए राजीव गांधी से पूछ लिया है?

सिंह पहले तो यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि वे जो कर रहे हैं, उसे चुनाव अभियान कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर साफ करते हैं कि प्रधानमंत्री को उन्होंने यह बता दिया था कि वे क्या करने जा रहे हैं। "मैं भारतीय जनता पार्टी के सामंतवाद के समानांतर कांग्रेस के समाजवाद का प्रचार करने जा रहा हूं। और इससे किसी कांग्रेसी को तो आतंकित नहीं ही होना चाहिए," वे दिलासा देते हैं।

लेकिन वोरा इससे आतंकित हैं और नहीं भी। उनका आतंक उनके साथी विधायकों की लगातार घटती संख्या को लेकर है। सौ से ज्यादा विधायक और मंत्री की हैसियतवाले निगम अध्यक्षों की अर्जुन सिंह की विजय यात्रा में उपस्थिति उन्हें हताश कर रही है। उनकी हताशा ज्यादा मुखरता से तब स्पष्ट हुई, जब २५ अप्रैल को अर्जुन सिंह के विधानसभा में पहुंचने पर उनका मेजें थपथपा कर स्वागत करने पर भाजपा विधायकों की आपत्ति और सिंह-समर्थकों के लगातार मेजें थपथपाते रहने के दौरान वोरा सदन में पहले तो चुपचाप बैठे रहे और बाद में उठकर चले गये। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे एक प्रतिनिधिमंडल से मिलना था।

इस बार आते ही वोरा को कई बार उठापटक का सामना करना पड़ा। सबसे पहले पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने तेंदू पत्ता नीति की वापसी और उस पर पुनर्विचार की घोषणा कर दी। इस पर जितना व्यापक हंगामा होना चाहिए था, उससे भी ज्यादा हुआ और आखिरकार वह नीति उन्हें वापस लेनी पड़ी। गरीब किसानों के लिए आसान शर्तों पर ट्यूबवैल लगाने की घोषणा भी इसी किरकिरी को धोने के लिए वोरा सरकार ने की थी, लेकिन अब तक उसका बहुत प्रचार नहीं हो पाया।

बहरहाल, मध्य प्रदेश में जंग अभी जारी है। कैरवा बांध के किनारे से भोपाल ताल के किनारे बने मुख्यमंत्री निवास तक अपनी-अपनी संभावनाएं और अपनी-अपनी आशंकाएं हैं। मोतीलाल वोरा को उनके संरक्षकों का खुला समर्थन न मिल सके, इसकी व्यवस्था सिंह के समर्थकों ने कर ली है और उधर वोरा ज्यादातर नये मंत्रियों से बनी अपनी टीम को संभालने के तनाव में दुबले हुए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चंदूलाल चंद्राकर दृश्य से लगातार अनुपस्थित हैं और इसे गमन के पहले का निर्वासन माना जा रहा है। पत्नी के इलाज के लिए सिंह अमरीका जायेंगे, लेकिन उसके पहले अपनी राजनीतिक हैसियत दर्ज कराने के लिए उनकी सघन सक्रियता के संभव नतीजों का सब इंतजार कर रहे हैं।

—विशेष प्रतिनिधि

रेलयात्रा : कितनी सुरक्षित ?

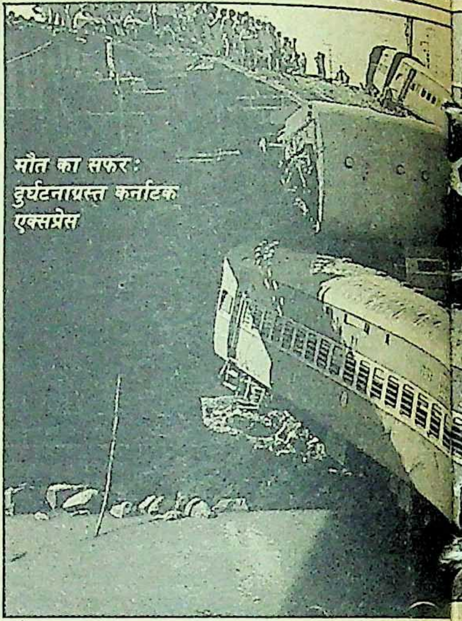
मौत का सफर: दुर्घटनाग्रस्त कर्नाटक एक्सप्रेस

१६ अप्रैल, १८५३ को भारतीय रेलवे का जन्म हुआ था। तब पहली भाप रेलगाड़ी ने बंबई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन से थाणे तक का ३४ किमी का फासला तय किया था, लेकिन १३६ वर्षों बाद आज ११२७० यात्री व मालगाड़ियां ७०९३ रेलवे स्टेशनों के बीच प्रतिदिन ६२ हजार किलोमीटर लंबे रेलमार्गों पर दौड़ रही हैं। इन रेलों में प्रतिदिन औसतन एक करोड़ आदमी सफर करते हैं और ८.५ लाख टन सामान इन रेलों द्वारा प्रतिदिन ढोया जाता है। भाप इंजिन के द्वारा २५ किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का सफर आज १३०-१४० किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलनेवाली डीजल व विद्युतचालित सुपरफास्ट ट्रेनों के युग में पहुंच गया है। लेकिन इस त्वरित विकास के साथ-साथ रेलयात्रा के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। यद्यपि रेलमंत्री माधवराव सिंधिया का कहना है कि रेल दुर्घटनाओं में ३२ से ४० प्रतिशत तक कमी आयी है। लेकिन वर्ष १९८७-१९८८ में ६०७ और १९८८-८९ में हुई ४८० रेल दुर्घटनाओं का असर आम जनता पर यह पड़ा है कि अब रेल के सफर के समय लोग आशंकित रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाये।

हाल ही १८ अप्रैल को झांसी के पास जिस तरह कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई, उससे तो पूरे देश में आतंक की लहर दौड़ गयी है। इस दुर्घटना का सबसे निराशाजनक पक्ष यह है कि सरकार अभी तक इस दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लगा पायी है। रोचक तथ्य यह है कि ८ जुलाई, १९८८ को केरल में हुई क्विलोन रेल दुर्घटना के जो कारण सरकार ने खोज निकाले हैं, उन पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। उस वक्त आईलैंड एक्सप्रेस पेरूमन रेलवे पुल से क्विलोन झील में गिर पड़ी थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अचानक आये एक भयानक चक्रवात ने रेलगाड़ी को उछालकर झील में गिरा दिया, लेकिन आसपास के लोगों और मौसम विभाग ने कहा है कि उस दिन उस क्षेत्र में चक्रवात आना तो दूर, पिछले डेढ़ सौ सालों से इस इलाके में कोई अंधड़ तक नहीं आया है। दरअसल, रेलवे विभाग सरलता से यह मानने को राजी नहीं होता कि रेल विभाग की गलती के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट ही बतलाती है कि १९८७-८८ में हुई ६०७ दुर्घटनाओं में ३७५ दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही और २४ दुर्घटनाएं रेल-लाइनों की गड़बड़ी के कारण हुईं। वर्ष १९८८-८९ में रेल—लाइनों की गड़बड़ी से होनेवाली दुर्घटनाओं की संख्या विगत वर्षों के मुकाबले २४ से बढ़कर ३८ हो गयी तथा ३० बड़ी रेल-दुर्घटनाओं में १९ दुर्घटनाओं के लिए रेलचालक की लापरवाही जिम्मेदार थी। गत वर्ष ७ अक्तूबर को मद्रास जानेवाली वृंदावन एक्सप्रेस बंगलोर छावनी में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। इस दुर्घटना के लिए भी रेलवे के पहियों की खराबी, तेज गति और खस्ताहाल रेलपटरियों को जिम्मेदार बताया गया था।

वस्तुत: जिस तेजी से रेलगाडियों की गति बढ़ाई जा रही है, उस तेजी से रेलपटरियों का सुधार नहीं हुआ। रेलवे मंत्रालय ने १९८५ में भारतीय रेलवे को २१ वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के काबिल बनाने के लिए एक १५ वर्षीय (१९८५-२०००) योजना बनायी थी, जिसके अंतर्गत न केवल सारी रेलपटरियों का सुधार होना है, बल्कि रेलवे के सारे ढांचे का कायाकल्प किया जाना है। लेकिन यह कार्य आसान नहीं है तथा इसके लिए रेलवे विभाग को ४६१५० करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो स्थिति यह है कि अभी तक भी आदिम जमाने के औजारों और तरीकों से रेलगाड़ियों और रेलपटरियों का रखरखाव किया जा रहा है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस संबंध में रेल कर्मचारियों से कोई चूक न हो। उन रेल पटरियों पर तो खतरे की आशंका बराबर बनी रहेगी, जहां रेलगाड़ियां एक सौ से एक सौ चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। वैसे भी रेल पटरियों का रखरखाव आसान काम नहीं है, जबकि रेलवे रिपोर्ट के ही अनुसार अप्रैल १९८८ में ही यह आकलन किया गया था कि तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के काबिल रेल पटरियों को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है कि १५३०० किलोमीटर रेलपटरी का पूरी तरह नवीनीकरण किया जाये।

यदि यह मान भी लिया जाये कि रेलवे विभाग पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त हो गया है, लेकिन तोड़फोड़ या आतंकवादी गतिविधियों से होनेवाली

रेल दुर्घटना

यात्रियों की उपेक्षा की कहानी

१८ अप्रैल को ललितपुर के निकट विशाखापत्तनम से नयी दिल्ली जा रही सुपरफास्ट कर्नाटक एक्सप्रेस की दुर्घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि रेल विभाग यात्रियों, रेल पटरियों और उनकी सुरक्षा के प्रति कितना सजग रहता है? ट्रेनचालक सतीश मिश्र और वीएस त्रिपाठी द्वारा दुर्घटना के कारणों का रहस्योद्घाटन करने के बाद रेल विभाग में हड़कंप मच गया है। बीना रेलवे स्टेशन पर ट्रेनचालक-द्वय ने इस तथ्य की लिखित जानकारी स्टेशन मास्टर को दी थी कि गाड़ी के तीन डिब्बों के शार्कस खराब हैं। गाड़ी बहुत उछाल ले रही हैं। डिब्बे काट दिये जायें। परंतु स्टेशन मास्टर ने असमर्थता व्यक्त की थी। बाद में उन्हीं डिब्बों की कपलिंग निकल गयी और डिब्बे पटरी से उतर गये। यही इस भीषण दुर्घटना का कारण बनी।

ललितपुर रेलवे स्टेशन से [illegible] होकर यह यात्री गाड़ी मात्र ढाई किलोमीटर दूर सिद्धन खनवा रेल पुलिया के निकट ही पहुंची थी कि दुर्घटना हो गयी। सरकारी स्तर पर दुर्घटना में मृतकों की संख्या ७० बतायी गयी है। लेकिन गैरसरकारी सूत्र, दुर्घटना स्थल पर पहुचे लोग व समाचार माध्यमों के अनुसार मृतकों की संख्या डेढ़ सौ से अधिक है। २१ बोगियोंवाली इस ट्रेन के ११ डिब्बे पटरी से उतरे थे। ९ डिब्बे पलटकर तीस फुट गहरे नाले में गिरे थे। इनमें से तीन डिब्बे तो एक दूसरे में पूरी तरह से समा गये थे। इसी से दुर्घटना की भयानकता का आभास मिलता है। कुछ डिब्बे पूर्णत: पानी में डूब गये थे।

दुर्घटना के तत्काल बाद ही दुर्घटनास्थल पर पहुंचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यात्रियों को बचाने में काफी मदद की। ललितपुर के जिलाधिकारी माजिद अली भी दुर्घटना के कुछ ही देर बाद वहां [illegible] गये थे, पर रेल विभाग की मदद सायं ७ बजे के

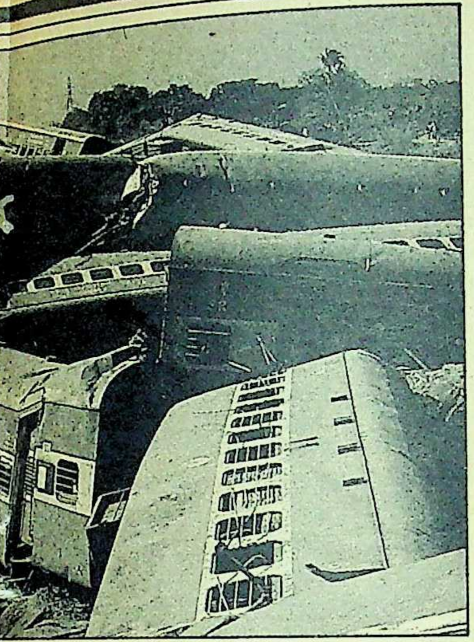

रेल दुर्घटनाओं को रोकने का सरकार के पास क्या उपाय है? कर्नाटक एक्सप्रेस की दुर्घटना के लिए तोड़फोड़ के षड्यंत्र की आशंका व्यक्त की जा रही है। रेलमंत्री माधवराव सिंधिया ने संसद में इस आशका पर जोर देते हुए बताया था, "जहां दुर्घटना हुई, उस पटरी पर कुछ चाबियां बिखरी हुई थीं और ये सभी चाबियां सहीसलामत थीं। हो सकता है, उनका वहां होना महज संयोग ही हो, लेकिन उनका सहीसलामत होना अपने आप में हैरानी की बात है। ये चाबियां स्लीपर को पटरी के साथ जोड़ने के काम आती हैं।" वास्तविकता तो यह है कि रेलवे विभाग के पास ऐसा कोई सुदृढ़ ढांचा नहीं है, जो तोड़फोड़ की कार्यवाहियों से रेलगाड़ियों को महफूज रख सके।

रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए दो प्रकार का पुलिस बल तैनात है। एक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) और दूसरा है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी)। आरपीएफ पूरी तरह से रेलवे विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और जीआरपी राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होती है। आरपीएफ का मुख्य कार्य रेलवे-संपत्ति और ढोये जा रहे सामान की रक्षा करना है। इस फोर्स को अधिकार है कि वह रेलवे संपत्ति की चोरी करनेवालों को देखते ही गोली मार दे, लेकिन किसी यात्री को लूटनेवालों को बंदी बनाने तक का अधिकार उसके पास नहीं है, यह कार्य जीआरपी करती है, जबकि जीआरपी के जवानों की संख्या आरपीएफ से कम है। वस्तुस्थिति तो यह है कि दोनों प्रकार के पुलिसबल के होते हुए न तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा हो पा रही है और न ही रेलगाड़ियों में होनेवाले अपराधों पर नियंत्रण। १९८३-८४ में रेलवे संपत्ति की चोरी के ८०८२५ मामलों के मुकाबले १९८७-८८ में ६८५०२ मामले दर्ज हुए। इस हिसाब से, तो लगता है कि रेलवे की संपत्ति की चोरी में कमी आयी है, लेकिन १९८३-८४ में जहां चोरी का ४१ प्रतिशत माल बरामद कर लिया गया था, वहीं १९८७-८८ में यह प्रतिशत घटकर २६ रह गया। स्पष्ट है अब चोर ज्यादा शातिर हो चुके हैं और आरपीएफ की मुस्तैदी में कमी आयी है। इस फोर्स के बलबूते तोड़फोड़ की कार्यवाही को रोक पाना संभव नहीं है, तो यात्रियों की सुरक्षा का कार्य जीआरपी के वर्तमान ढांचे के बूते की बात नहीं है।

यात्रियों की निरापद सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी है कि जितना ध्यान रेलवे के सुधार पर दिया जा रहा है, उससे कहीं अधिक ध्यान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का कायाकल्प करने पर भी दिया जाये। **—विनोद मिश्र**

गिद्ध: आहतों का लुटेरा

संयोग: डिब्बा काटकर निकाली गयी एक महिला यात्री

बाद पहुंची, जबकि दुर्घटना २ बजकर ४० मिनट पर हुई थी। यह तो गनीमत थी कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ब्रिगेडियर बत्रा सेना के जवानों के साथ घायलों की सहायता के लिए पहुंच गये थे, अन्यथा कई और जानें जातीं। सेना के जवानों ने ही मृतकों और घायलों के शरीर से आभूषण व उनके सामान लूटनेवालों को घेरा डाल कर पकड़ा। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक ने स्वयं यह स्वीकार किया कि एक सिपाही जिसने घायल यात्रियों को लूटा था, के पास सोने की १४ जंजीरें और काफी नकदी बरामद हुई।

जिस समय यह दुर्घटना हुई, उस समय रेल राज्यमंत्री माधव राव सिंधिया ग्वालियर में अपनी दस जिलों की संपर्क-यात्रा शुरू करने की तैयारियों में लगे थे। उल्लेखनीय है कि इस संपर्क-यात्रा की योजना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा और माधव राव सिंधिया ने मध्यप्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से बनायी थी।

फिलहाल सिंधिया दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद रात लगभग एक बजे घटनास्थल पर पहुंचे। वे अपने साथ ग्वालियर से चहेते पत्रकारों की टीम भी लाये थे। हालांकि इसके पूर्व दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में यह घोषणा की जा चुकी थी कि रेल राज्यमंत्री घटना-स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। सिंधिया के घटना-स्थल पर पहुंचने पर जब रेल विभाग के अधिकारी घायलों की सहायता छोड़ उनकी आवभगत में जुट गये, तो सेना के अधिकारियों ने उन्हें खूब फटकार सुनायी। इसके बाद सिंधिया ने किसी भी छायाकर को अपना फोटो नहीं खींचने दिया। जो भी हो सिंधिया ने घायलों को घटना स्थल पर ही सहायता राशि दिलायी।

१९ अप्रैल की सुबह दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के रिश्तेदारों का तांता झांसी रेलवे स्टेशन पर लगा था। लोग अपने संबंधियों की जानकारी मांगते हुए रो-कलप रहे थे, पर रेल अधिकारियों ने न तो घायलों और मृतकों की कोई सूची टांगी और न ही समाचार माध्यमों के जरिये इसकी जानकारी दी। जिस समय यह दुर्घटना हुई, रेल विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी झांसी में नहीं था। खुद डीआरएम यमनलाल काक ५ घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंचे, क्योंकि वे ग्वालियर में रेल राज्यमंत्री की आवभगत में व्यस्त थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी दुर्घटना के एक दिन बाद १९ अप्रैल को घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को उदारता का नाटक करते हुए पन्द्रह हजार तथा घायलों को पांच हजार रुपए देने की घोषणा की।

दुर्घटनाग्रस्त कर्नाटक एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों का कहना है कि ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी, अचानक ब्रेक लगने का सा झटका लगा और फिर जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद चारों ओर चीख-पुकार और रोने कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। यात्रियों का यह भी कहना है कि ट्रेन के पिछले डिब्बे इटारसी से ही उछाल ले रहे थे। रेल राज्यमंत्री सिंधिया ने इस दुर्घटना में तोड़फोड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। दुर्घटना की जांच २१ अप्रैल से मध्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने शुरू कर दी है। इस जांच का फल क्या निकलेगा, यह तो भविष्य ही तय करेगा। जब पहले हुई दुर्घटनाओं में दिये गये सुरक्षा उपायों को अमल में नहीं लाया जायेगा, तो दुर्घटनाएं कैसे रुकेंगी, अहम सवाल है। रेल विभाग की लापरवाही के कारण जिन यात्रियों की जानें गयी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

—लखनऊ ब्यूरो

छाया: एमखान 'पप्पू'

आम चुनाव के लिए डेढ़ लाख इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें

आगामी आमचुनाव में १५० संवेदनशील संसदीय चुनाव क्षेत्रों में घपलों को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने डेढ़ लाख इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के निर्माण का आदेश दिया है। प्रत्येक मशीन की कीमत करीब पांच हजार रुपए होगी।

विबलडन टेनिस की इनामी राशि २६ लाख ३० हजार ३०८ पौंड (४,४७१.५० डालर या करीब सात करोड़ रुपए) से बढ़कर ३० लाख ६३ हजार ४९ पौंड (५३२९७०० डालर या करीब ८ करोड़ रुपए) कर दी गयी है।

नयी शोधों ने पुष्टि की है कि कृष्ण तुलसी के सेवन से दिल की बीमारियों का निराकरण संभव है। आयुर्वेद शास्त्र में इसे हृदय संतमनम (दिल के दौरे) रोग की औषधि कहा गया है।

अब ईरान में फैशनपरस्त महिलाओं को ७४ कोड़ों तक की सजा मिल सकती है।

'कल' नामक एक फिल्म शीघ्र ही प्रदर्शित होगी। इसकी विशेषता यह है कि इस फिल्म के कलाकारों ने ही (दूरदर्शन धारावाहिक 'नुक्कड़' के कलाकार) इसमें अपनी पूंजी लगायी है और मुख्य पात्र की भूमिका के लिए अमोल पालेकर ने सिर्फ एक सौ पच्चीस पैसे बतौर पारिश्रमिक लिये हैं।

अब ईरान में महिलाएं यदि लिपिस्टिक, पाउडर आदि से मेकअप करेंगी या बालों को खुला रखेंगी या चुस्त कपड़े पहनेंगी या मर्दों की ओर देखती पायी जायेंगी, तो उन्हें ७४ कोड़ों तक की सजा मिल सकती है। 'इस्लाम' की रक्षा के लिए ईरान सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून वहां गत २१ अप्रैल से लागू हो गया है।

गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में इस वर्ष दो नये कीर्तिमान दर्ज हुए हैं। एक है, सात टन वजनी कैडिलेक एल्डिराडो १९८२ माडल की २१.९३ मीटर लंबी कार। १८ पहियों की इस कार में रेफ्रीजरेटर, नहाने के टब, टेलीविजन वीडियो डैक, टेलीफोन और २० लोगों के बैठने का सैलून है और इसका एक दिन का किराया पांच हजार अमरीकी डालर अर्थात १५ हजार रुपए है। इसके पूर्व जापान ने २१ मीटर लंबी कार बनायी थी। दूसरा कीर्तिमान ७२८ पुर्जों से ९ साल में बनी १८ कैरेट सोने की घड़ी ने बनाया है, जिसने २७ लाख ४० हजार डालर (४ करोड़ ११ लाख रुपए) में बिककर सबसे महंगी घड़ी का खिताब पाया। इसके पूर्व की सबसे महंगी घड़ी १२ लाख डालर (१ करोड़ ८० लाख) में बिकी थी।

पांडिचेरी में अब एक ऐसी फैक्ट्री लग रही है जो मनुष्य के बालों से दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में काम आनेवाला एमीनो एसिड बनायेगी। भारत में अपने किस्म की यह अकेली फैक्ट्री है। इससे पहले मनुष्य के बाल जापान को निर्यात कर दिये जाते थे, जिससे एमीनो एसिड बनाकर जापान इसे विश्व बाजार में बेचता था।

आगामी आमचुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने दूरदर्शन एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए ३२ कार्यक्रमों के प्रसारण की एक विशेष योजना तैयार की है। १७ करोड़ के खर्चे से तैयार ये कार्यक्रम कांग्रेस-इ सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे और लगातार छह मास तक दिखाये जायेंगे।

युरोप की गैरसरकारी संस्थाओं के एक संगठन के लिए तैयार की गयी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी पर महिलाओं की जनसंख्या ५० प्रतिशत है और वे दो तिहाई काम करती हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले में कुल आय का सिर्फ दस प्रतिशत और पृथ्वी पर उपलब्ध साधन स्रोतों का एक प्रतिशत प्राप्त होता है।

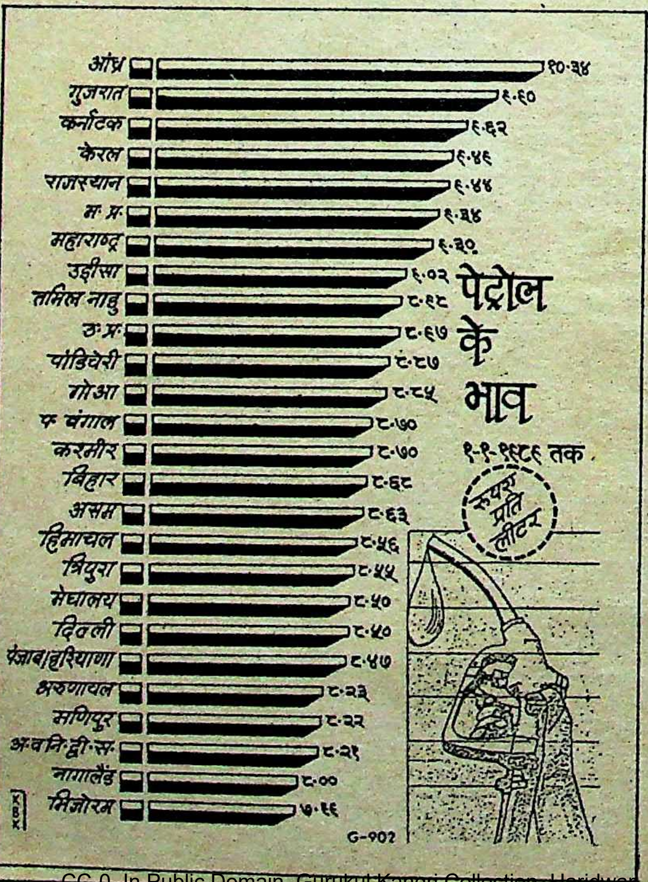

फिलीपींस के निष्कासित राष्ट्रपति मारकोस पर कुल २६ करोड़ ८० लाख डालर (करीब ४ अरब, दो करोड़ रुपए) के गोलमाल का आरोप लगा है। इसमें से १० करोड़ ३० लाख डालर तो उन्होंने फिलीपींस के सरकारी खजाने से चुराये थे और १६ करोड़ ५० लाख डालर न्यूयार्क के बैंकों से लिये थे।

देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अब उनकी संख्या ३ करोड़ से अधिक हो गयी है। दिल्ली के अमीरों में मधुमेह के रोगियों की संख्या ढाई प्रतिशत से बढ़कर ११ प्रतिशत हो गयी है।

देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या ३ करोड़ से अधिक हो गयी है।

हर मौसम में कहीं भी अपनी रक्षा में समर्थ काक्रोच (तिलचट्टों) का इतिहास ४० करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन अब उनका विनाश करने के लिए आस्ट्रेलिया के एक ३४ वर्षीय किसान ग्रेग जेफ्रीज ने 'इलेक्ट्रानिक काक्रोच जैपर' नामक मशीन का आविष्कार किया है। ९५ डालर (१४२५ रुपए) कीमत की वीडियो कैसेट जैसी यह मशीन विद्युत तरंगें छोड़कर काक्रोचों का विनाश करती है।

भरतपुर के प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री वेदज्ञ डा० मनोहरलाल गुप्त ने गहन शोध के बाद निष्कर्ष निकाला है कि धरती पर मानव की उत्पत्ति आज से करीब ३०५०० वर्ष पूर्व हुई थी और वेदों की रचना १६५०० वर्ष पूर्व।

भारत सरकार ने सऊदी अरब में बढ़ी महंगाई को ध्यान में रखकर हजयात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा २३ हजार रुपए से बढ़ाकर २४ हजार कर दी है।

—संयोजन : विनोद मिश्र

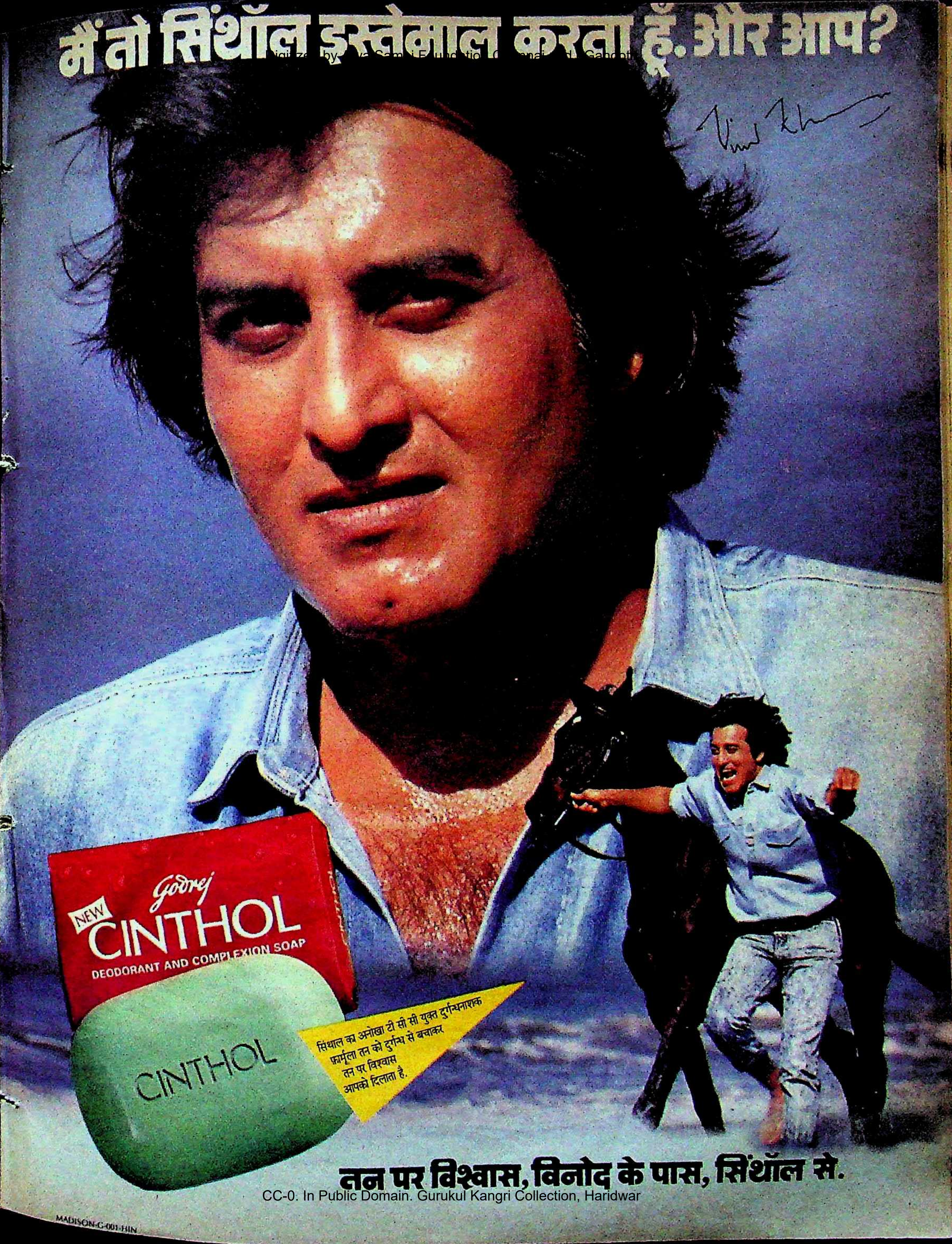
मैं तो सिंथॉल इस्तेमाल करता हूँ. और आप?
Vinod Khanna
Godrej
NEW
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
CINTHOL
सिंथाल का अनोखा टी सी सी युक्त दुर्गन्धनाशक
फार्मूला तन को दुर्गन्ध से बचाकर
तन पर विश्वास
आपको दिलाता है.
तन पर विश्वास, विनोद के पास, सिंथॉल से.
MADISON-G-001-HIN

कश्मीर

देश पर पाकिस्तान का अघोषित हमला

क़यामत बरपा करने के लिए दिन तो चुना गया था १३ जुलाई, १९९०, लेकिन भेद इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में ही खुल गया। दरअसल, पाकिस्तान की साजिश थी कि ५००० कश्मीरी उग्रपंथी युवकों को आतंक में दीक्षित और अत्याधुनिक शस्त्रों से सज्जित करके १३ जुलाई, १९९० को उतारा जाये और पूरे कश्मीर में अराजकता फैला दी जाये। लेकिन अप्रैल के शुरू में कुछ अतिउत्साही प्रशिक्षु आतंकवादियों ने अपनी कलाश्नीकोव राइफलों के घोड़े दबा दिये और पुलिस से घमासान मुठभेड़ कर बैठे। इससे पता चला कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर रहा है और इस काम के लिए उसने करोड़ों रुपए का बजट रख छोड़ा है। इसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे हिंदुस्तान की लड़ाई कश्मीर की गलियों में लड़ रहे हैं। यद्यपि पाकपरस्त तत्व लगातार कश्मीर घाटी में उपद्रव करते रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति भयानक है। अब बमों के धमाकों, भवनों और पुलों को उड़ाने की घटनाएं वहां आम हो गयी हैं। पाकिस्तान के भारतस्थित राजदूत ने इस बात से इनकार किया है (देखिए साक्षात्कार) कि कश्मीर की घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन इस समय जैसी वहां स्थितियां हैं, उनसे स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठिये भेजने का क्रम शुरू करके देश पर एक प्रकार से अघोषित हमला बोल दिया है। सवाल उठता है कि कश्मीरी युवकों को पाकपरस्त बनाने के लिए कौन सी स्थितियां जिम्मेदार हैं? यद्यपि फारूक अब्दुल्ला ने हाल में अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके अपनी सरकार को सशक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन क्या वे उन स्थितियों को बदल पायेंगे जो राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और भयानक बेरोजगारी ने उत्पन्न की हैं? देश की एकता और सुरक्षा के लिए घातक स्थितियों का व्यापक अध्ययन करके कश्मीर से लौटे *आरके मिश्र* की रपट :

कश्मीर को प्रकृति ने खुबसूरती बख्शी है और भू-राजनीति ने उसे नाजुक बनाया है। लेकिन इस समय कश्मीर विरह से अलसायी एक रूपसी की तरह है। यह तुनकमिजाज रूपसी अपने पड़ोसी की ओर आंखें मटका रही है, ताकि उसका ईर्ष्यालु और लापरवाह शौहर समय रहते उसकी सुध ले सके। उसका हिमधवल वक्ष जब उसांसें भरता है, तो घाटी में भूचाल आ जाता है। उसके आंसू खून में बदल जाते हैं। दरअसल वह अपने खिदमतगार से नाखुश है और शौहर पर क्रुद्ध है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इस बार बात हद से ज्यादा बढ़ गयी है।

तीन बार पिटा हुआ शोहदा-पाकिस्तान-बगीचे की दीवार के पार अपनी लोलुप दृष्टि गड़ाये बैठा है। इस बार उसकी चालें बेहद घातक हैं। वह दीवार पर फैली लताओं में ही इसे कैद कर देना चाह रहा है।

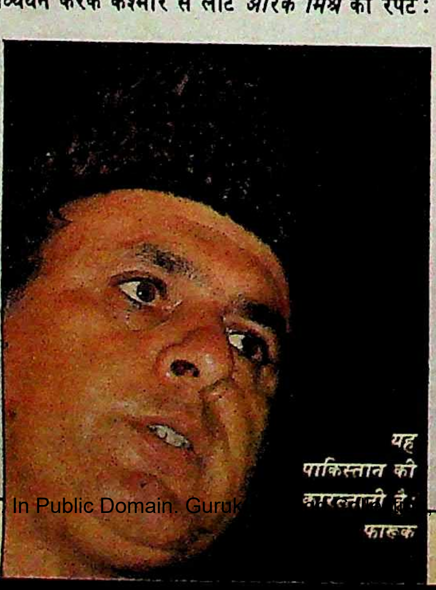

यह पाकिस्तान की कारस्तानी है : फारूक

भेद खुल गया : उसने कयामत बरपा करने के लिए १३ जुलाई, १९९० का दिन चुना था। तब तक ५००० गुमराह कश्मीरी युवकों को सीमा पार प्रशिक्षित करके घाटी में वह ठूंस देना चाहता था, ताकि इशारा पाकर वे कहर ढा सकें। साजिश के तहत उन्हें व्यापक तोड़फोड़ और विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न करनी थी।

लेकिन यह साजिश उस समय विफल हो गयी, जब अप्रैल, १९८९ के पहले हफ्ते में ही आतंक का प्रशिक्षण ले रहे कुछ जत्थों ने श्रीनगर की गोलियों में अति उत्साह में अपनी कलाश्नीकोव राइफलों के घोड़े दबा दिये और पुलिस से मुठभेड़ शुरू कर दी। वैसे भावी खतरे का पूर्वसंकेत १६ सितंबर, १९८८ को ही मिल गया था, जब पुलिस उपमहानिदेशक

CC-0. In Public Domain. Guruk... Haridwar

सशस्त्र मुठभेड़: श्रीनगर में दंगाइयों से मुकाबला करती पुलिस

एएम वटाली पर कातिलाना हमला हुआ था। इस घटना में एजाज दर नामक एक आतंकवादी मारा गया था।

मामले की चरम परिणति इस वर्ष अप्रैल में हुई। इस समय बिना किसी जाहिर कारण के आतंकवादियों ने तीन दिन के बंद का आयोजन किया था। इस दौरान श्रीनगर के गली-कूचों में पुलिस और शस्त्रसज्जित युवकों के बीच जमकर झड़पें हुईं। हिंसा कस्बों की सीमा पार कर नये-नये इलाकों तक पहुंच गयी। आग में घी का काम किया अनंतनाग में पुलिस संरक्षण में ७० वर्षीय गुलाम मोहम्मद शाह की मौत ने। शाह के एक पुत्र—सईद अहमद—मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट (एमयूएफ) के विधायक हैं और दूसरा—शब्बीर शाह—कुख्यात आतंकवादी है। खबर है कि ईद के बाद ४१ दिन के बंद की योजना भी है।

बम के धमाकों की बाढ़: पहले घाटी में गाहे-बगाहे बम के धमाके हो जाते थे, लेकिन अब तो यह रोजमर्रा की चीज हो गयी है। यह बात आश्चर्यजनक है कि जिस कश्मीर में बंदूक रखना रबैल रखने से ज्यादा बुरा माना जाता था, आज उसी कश्मीर में कलाश्नीकोव राइफलें आम हो गयी हैं।

हिंसा का आलम यह है कि सरकारी सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में इस साल जनवरी से ६ मार्च के बीच ६१ बमों के धमाके हुए। जिनमें से २३ बम श्रीनगर जिले में फूटे, १२ बम अनंतनाग में, १० पूंछ इलाके में, छह डोडा में, तीन बम कुपवाड़ा जिले में, दो-दो बम जम्मू और उधमपुर में और एक-एक बम लेह, कठुआ और राजौरी में फूटे। इसी दौरान १६ लोगों की जानें गयीं और ९४ लोग घायल हुए, जिनमें १८ पुलिसजन भी शामिल हैं। यही नहीं, इस बीच कुल १५५ लोगों को आतंकवादी एवं विध्वंसक कार्रवाई निरोधक अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया और ८ लोगों को जनसुरक्षा अधिनियम के तहत कैद में रखा गया। लेकिन जनवरी से ६ मार्च के बीच के उपर्युक्त आंकड़े अप्रैल महीने में देखते-ही-देखते दो गुना, तीन गुना हो गये। अप्रैल में सोपोर इलाके में एक ही दिन में चार बम फूटे।

सनसनीखेज बयान: इस बीच मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान देकर, सनसनी फैला दी कि श्रीनगर की सड़कों पर वे पाकिस्तान से जूझ रहे हैं। हालांकि कश्मीर घाटी के विपक्षी नेता सिरे से फारूक की बात को गलत बताते हैं। मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट के मौलवी अब्बास अंसारी फारूक के बयान पर टिप्पणी करते हैं, "यह कोई नयी बात

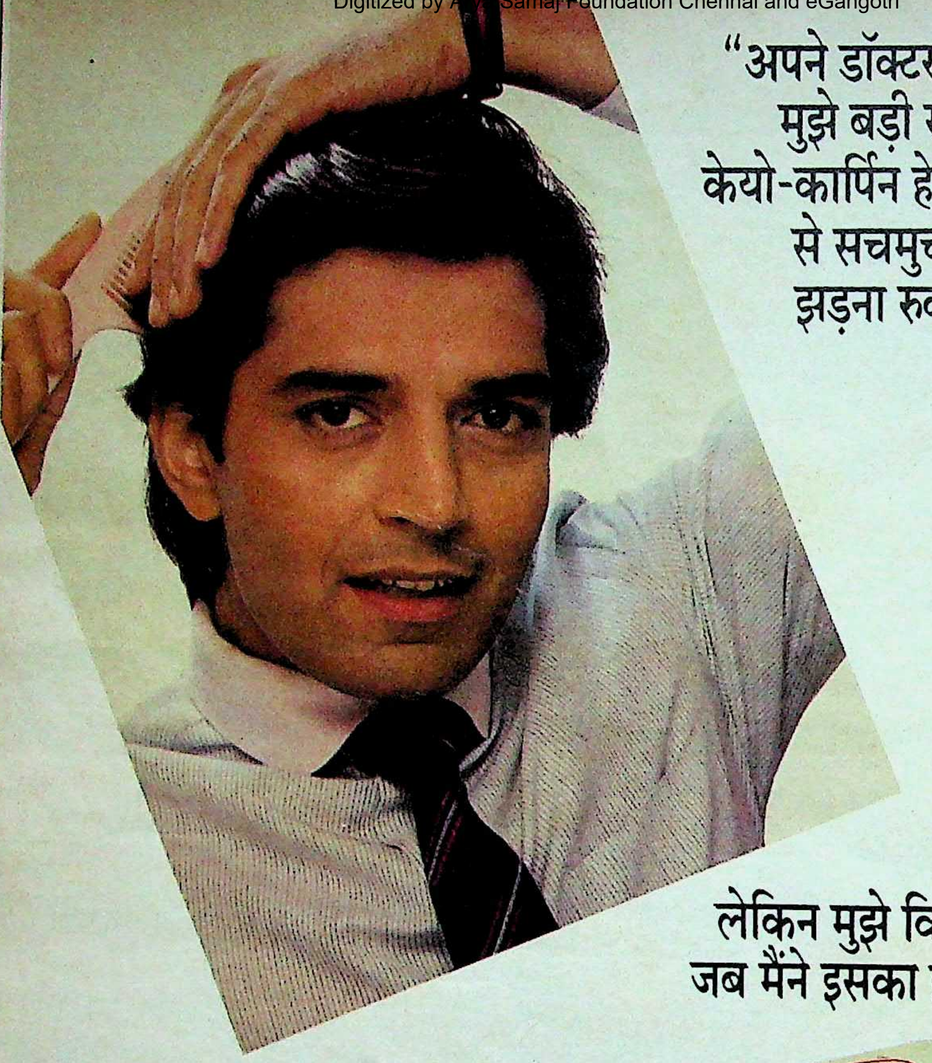

"अपने डॉक्टर से यह जानकर
मुझे बड़ी खुशी हुई कि
केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र
से सचमुच बालों का
झड़ना रुक जाता है।

लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ
जब मैंने इसका इस्तेमाल किया।"

"मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र*, व्यापक गवेषणा पर आधारित एक अपूर्व वैज्ञानिक फार्मूले से बना है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बालों की जड़ों को मज़बूत करनेवाले सभी आवश्यक प्रोटीन तत्व, को-एन्जाइम और विटामिन भी उपलब्ध करता है।

मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे बालों का झड़ना निश्चितरूप से रोक दिया है और साथ ही रूसी भी खत्म हो गई है।"

देखिए, गवेषणा-रिपोर्ट से उद्धृत एक अंश:

"सभी मामलों में रूसी के सम्पूर्ण खात्मे के साथ ६६.६६% मामलों में शानदार एवं ३३.३३% में बढिया नतीजा हासिल हुआ और बालों का झड़ना तो लगभग शत प्रतिशत रुक गया...इसलिए, यह कहा जा सकता है कि केयो-कार्पिन हेयर वाइटालाइज़र की सफलता-दर शत प्रतिशत है।"

इंडियन मेडिकल गज़ट ११८ २२३ (१९८४)

Dey's
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
Keo-Karpin
HAIR VITALIZER
CONTAINING PROTEIN, VITAMINS AND CO-ENZYMES
DEY'S MEDICAL STORES LTD.

बालों का झड़ना रोकने का
प्रमाणित वैज्ञानिक तरीका।

Dey's® दे'ज मेडिकल की संभाल, आपका भरोसा।

*यह शृंगार सामग्री नहीं है।

DMHV-4

Gangotri

हिंसा का तांडव: दंगाइयों से निबटने में विफल पुलिस

नहीं है। सरकार अपनी कमजोरियों को ढांकने के लिए हमेशा इसी तरह के बयानात देती आयी है, ताकि लोग उसकी कमजोरियों पर ध्यान न देकर पाकिस्तानी खतरे पर माथापच्ची करें।" इसी तरह मीरवाइज मौलवी फारूक कश्मीर सरकार पर छींटाकशी करते हुए कहते हैं, "पूरी तरह से निकम्मी सरकार सरकारी खजाने को लूट रही है और इस तरह के बयानात से दिल्ली का दखल बढ़ा कर मजीद मदद का माहौल बना रही है।" यही नहीं, काजी निसार, दक्षिण कश्मीर के मीरवाइज और उम्मते इस्लामी संगठन के प्रमुख तो फारूक अब्दुल्ला के बयान को 'सफेद झूठ' की संज्ञा देते हैं। विपक्षी नेता सवाल करते हैं कि जब फारूक सरकार का यह दावा है कि पाकिस्तान से प्रशिक्षित उग्रवादी कलाश्नीकोव राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रशासन यह क्यों नहीं बताता कि ऐसे घातक हथियार के हमलों से कितने पुलिसवालों को जान से हाथ धोना पड़ा? वे पूछते हैं कि क्या कश्मीरी पुलिस की कदीमी ३१० मस्केट (छोटी बंदूक) तथा ३०३ राइफलें कलाश्नीकोव राइफलों के सामने ठहर सकती हैं? विपक्षी नेताओं की इस बात में दम नजर आता है, क्योंकि सरकार और प्रशासन इस बात का शोर मचा रहा है कि उग्रवादी कलाश्नीकोव राइफलों से हमला कर रहे हैं, किंतु अभी तक के भीषण संघर्षों में किसी पुलिसकर्मी के मरने की खबर नहीं है।

ऐसे में सच क्या है, इसका पता लगाना आसान बात नहीं। किंतु विपक्ष के अपने तर्क हैं। उसके अनुसार, "हम इस बात से इनकार नहीं करते कि वक्त के मारे कुछ कश्मीरी नौजवान दहशतपसंदी पर आमादा हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर उनके मुस्तकबिल को अंधेरे गटर में किसने झोंका है? क्या इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं? हमारा तो मानना है कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार ही मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार है।" दूसरी ओर कलाश्नीकोव राइफलों से संघर्ष में पुलिस के न मारे जाने के बारे में एक पुलिस अधिकारी जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, कहते हैं, "असल में आटोमेटिक कलाश्नीकोव राइफलों की मारक दूरी सिर्फ ८० मीटर ही होती है और अब तक जो भी वार हुए हैं, वे २५० से ५०० मीटर की दूरी से हुए हैं।"

पाकिस्तानी साजिश: परस्पर विरोधी बयान अपनी जगह हैं, किंतु इस सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान निश्चित रूप से घाटी में आग को हवा दे रहा है। विश्वस्त सूत्रों से मिली खबर के अनुसार १९८४-८५ में पाकिस्तान में उच्च स्तर पर कश्मीर संबंधी नीति निर्धारित की गयी थी। खुफिया विभाग की रिपोर्ट भी हाशिम कुरैशी की आवाजाही को उसी नीति से जोड़ती है। उल्लेखनीय है कि हाशिम कुरैशी कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का अग्रणी है जो फिलहाल हालैंड में बस गया है।

कुरैशी का नाम तो उसी समय प्रकाश में आया था, जब वह इंडियन एअरलाइंस के एक जहाज को अगुवा करके पाकिस्तान ले गया था। कुरैशी कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से आजाद कराने का दम भरता है। श्रीनगर के मशहूर साप्ताहिक 'चट्टान' में लिखे अपने लेखों में उसने बताया है कि पाकिस्तानी सेना की खुफिया ने १९८४ में कश्मीर के लिए नयी हमलावर योजना तैयार की थी। कुरैशी के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया की नयी योजना के अंतर्गत पाकिस्तान तथा पाकिस्तानी कब्जेवाले कश्मीर में कश्मीरी नवयुवकों के प्रशिक्षण हेतु कैंप लगाया जाना शामिल था। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की योजना भारतीय कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट के जरिये कश्मीरी नवयुवकों का भारतविरोधी जेहन बनाना और उन्हें पाकिस्तानी कैंपों में प्रशिक्षण लेने के लिए फुसलाना था। इस काम के लिए रणनीति तैयार करने के मकसद से १९८४ के मध्य से ही पाकिस्तान ने लिबरेशन फ्रंट के चुनिंदा नेताओं को दावत दी थी। पाकिस्तान की दावत पर कुरैशी के ही नेतृत्व में चार सदस्यीय दस्ता पाकिस्तान गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय कुरैशी फ्रंट की संगठनात्मक समिति का अध्यक्ष था। लेकिन उस समय पाक सेना और कुरैशी के बीच तीन महीने तक चली समझौता-वार्ता विफल हो गयी। पाकिस्तानी सेना चाहती थी कि कुरैशी अपना काम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह के लिए केवल वालंटियर भेजने तक सीमित रखे। उनको प्रशिक्षण, हथियार और हुकुम देने का काम पाकिस्तानी सेना अपने अधीन रखना चाहती थी। इस पर कुरैशी तैयार नहीं हुआ। नतीजतन माहौल कुरैशी के खिलाफ हो गया और उसे भागकर एम्सटर्डम में पनाह लेनी पड़ी।

कुरैशी के बाद मकबूल भट्ट ने लिबरेशन फ्रंट का नेतृत्व संभाला और मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में डकैती और कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी गयी, तो अमानुल्लाह खान ने आगे बढ़कर लिबरेशन फ्रंट की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद पाकिस्तान के साथ इन तत्वों का नया समझौता हुआ और अक्तूबर १९८७ से उस पर अमल शुरू हुआ।

लिबरेशन फ्रंट के मददगार: यहां पर उन ताकतों का जिक्र करना जरूरी है, जिनकी लिबरेशन फ्रंट को मदद मिलती रही है। 'महाजे-आजादी' एक ऐसा संगठन था, जिसने अपना एकमात्र लक्ष्य कश्मीर की आजादी घोषित किया। हालांकि यह संगठन हमेशा कागज पर ही रहा। १९८६ के आसपास पीपुल्स लीग वजूद में आयी। फारूक रहमानी, शब्बीर शाह और अजीज शेख (वर्तमान महासचिव) इस संगठन के अग्रणी रहे। फारूक रहमानी और शब्बीर शाह में आपसी टकराहट हो गयी, तो शब्बीर के समर्थकों ने इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग बना ली। १९८७ में सूफी मोहम्मद अकबर की मौत के बाद मोहम्मद आजम इंकलाबी जम्मू-कश्मीर महाजे आजादी का प्रमुख बना। इंकलाबी ने दहशतपसंदी में काफी नाम कमाया है। फिलहाल वह बड़ी तादाद में उग्र नौजवानों का सरपरस्त बना हुआ है। यह संगठन काफी जड़ें भी पकड़ रहा है।

कुछ विश्वस्त सूत्रों का मानना है कि केवल पाकिस्तान ही नहीं, ईरान और सऊदी अरबिया भी मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट को मदद कर रहे हैं। यह मदद उस समय शुरू हुई, जब विधानसभा चुनाव से पहले फ्रंट एक ताकतवर संगठन के रूप में उभरा। इस संबध में सूत्रों का कहना है कि ईरान ने शिया-सुन्नी को करीब करने की मुहिम तेज करने के नाम पर मौलवी अब्बास असारी को जनवरी १९८८ में ईरान बुलाया था और वीआईपी सम्मान दिया था। उसी समय उनको यह इशारा किया गया था कि

रोजमर्रा के दृश्य: बमविस्फोट और पत्थरबाजी

कश्मीर घाटी

विकास की नयी संभावनाएं

"कश्मीर में बिंजली की हालत अगले साल की शुरुआत तक सुधर जायेगी और राज्य के अन्य कई क्षेत्रों में भी सुधार आयेगा।" यह उम्मीदं जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव मूसा रजा ने जाहिर की है।

वे बताते हैं कि पिछले आठ सालों में कई परियोजनाएं शुरू की गयीं, लेकिन इनमें से अधिकांश अब पूरी हो रही हैं। वे कहते हैं, "आपको समझना चाहिए कि घाटी (कश्मीर) में साल में सिर्फ छह महीने काम होता है। जहां कश्मीर घाटी को ४५० मेगावाट बिजली की जरूरत है, वहां हमारे पास २१० मेगावाट की ही क्षमता है। यह भी भयंकर जाड़े के महीनों में घटकर सिर्फ ११० मेगावाट रह जाती है। आम मौसम में जहां २९ लाख यूनिट बिजली मिलती है, वहां जाड़ों में हमें सिर्फ १२ लाख यूनिट ही मिल पाती है।"

मुख्य सचिव के आशावान होने का एक मजबूत आधार यह है कि ऊपरी सिंध की परियोजना इस साल के अंत तक पूरी हो जायेगी। रजा का कहना है कि इस साल दिसंबर तक हमें अलग से १२५ मेगावाट बिजली मिलने लगेगी! जो १६५ करोड़ रु० की लागत से चलाये गये 'आपात विद्युत उत्पादन कार्यक्रम' (जिसके तहत ऊपरी सिंध परियोजना है) के कारण संभव होगा।

रजा बताते हैं कि सलाल से श्रीनगर तक की ४४० केवीए लाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। यह लाइन समूची पर्वत-श्रेणी को पार कर कश्मीर घाटी में बिजली पहुंचायेगी। इसके लिए रूस के साथ दोतरफा करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं और इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। १३६ करोड़ रु० की इस परियोजना के तहत बिजली के ग्रहण व पुर्नवितरण के लिए दो बिजलीघरों का निर्माण शीघ्र शुरू किया जायेगा जो १९९२ तक पूरा हो जायेगा।

एक सवाल के जवाब में मूसा रजा स्वीकार करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र ने भी राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कोई खास योगदान नहीं किया। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर की आबादी देश की कुल आबादी का एक प्रतिशत है और पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र में ८० हजार करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, इस हिसाब से जम्मू-कश्मीर

में भी इस पूंजी का एक प्रतिशत अर्थात ८०० करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लगाया जाना चाहिए। लेकिन कश्मीर घाटी में १४० करोड़ की लागत से एचएमटी का एक कल-पुर्जे बनाने का कारखाना १५ वर्ष पहले स्थापित हुआ था। कश्मीर के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का यही एकमात्र योगदान है।

मूसा रजा

मुख्य सचिव का कहना है कि कश्मीर घाटी में इधर शिक्षा का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ और साक्षरता का प्रतिशत ११ से बढ़कर २६ हो गया है। पूरे देश में इस दौरान शिक्षा के प्रसार की गति भी कमोवेश यही (२५ से ३७ प्रतिशत) रही है। बहरहाल, जिस तेजी से कश्मीर घाटी में शिक्षा का प्रसार हुआ, उस तेजी से यहां रोजगार के अवसर नहीं बढे। भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है। गत मास एक विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम प्रदेश मे रोजगार के अवसरों का जायजा ले चुकी है।

मूसा रजा बताते हैं कि प्रदेश में पहली बार शिक्षा के विकास पर १०९ करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनायी गयी है, जबकि गत वर्ष शिक्षा पर किया गया खर्च मात्र ३५ करोड़ था। १६०० नये स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं, ४००० स्कूलों का नवीनीकरण किया जा रहा है, २ नये कालेज और १३ नये औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। सुप्रिटेंडेंट इंजीनियरों सहित ४५ इंजीनियरों को निलंबित किया जा चुका है।

उन्होंने जानकारी दी कि श्रीनगर शहर के सुनियोजित विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है कि श्रीनगर के कुल ६६८ महल्लों में से २२८ महल्ले सिर्फ ८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही सिमटे हुए हैं, जबकि इन महल्लों में श्रीनगर की आधी आबादी निवास करती है। यहां आबादी की सघनता का आलम यह है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ४१ हजार लोग रहते हैं और जन सुविधाओं की हालत यह है कि इन क्षेत्रों में न तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है, न ही कोई सार्वजनिक वाचनालय या टेलीफोन बूथ। ■

कश्मीर में क्या होना चाहिए।

इस बीच लंदन में एक भारतीय राजनीतिज्ञ का कत्ल हो गया, जिसके कारण अमानुल्लाह खान को इंग्लैंड से बाहर कर दिया गया। इस घटना को पाकिस्तानी खुफिया विभाग ने काफी तूल दिया और अंततः अमानुल्लाह खान को पाक अधिकृत कश्मीर में जमा दिया। अमानुल्लाह को इसलिए भी तरजीह दी गयी, क्योंकि वह कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का हिमायती है, जबकि हाशिम कुरैशी कश्मीर की पूर्ण स्वतंत्रता का झंडाबरदार है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां एफआईयू (फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट) तथा आईएसआई (इंटर सर्विस इंटेलिजेंस) कई स्वतंत्र जरियों से कश्मीर में सक्रिय हैं। पाक खुफिया एजेंसियों द्वारा खड़े किये गये घाटी में सक्रिय इन गुटों को एक दूसरे की कोई जानकारी नहीं है।

बहरहाल जब अमानुल्लाह खान कश्मीर को पाकिस्तान के सुपुर्द कराने का हामी हो गया, तो उसने शब्बीर शाह और आजम इंकलाबी से तालमेल बिठाया तथा यह योजना तैयार हुई कि कश्मीरी नौजवानों को सीमा के पार पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाये। सूत्रों के अनुसार कश्मीरी नौजवानों का पहला दस्ता गत वर्ष (१९८८) मार्च में प्रशिक्षण हेतु रवाना किया गया। तब से लगातार २०-२०, २५-२५ की तादाद में कश्मीरी नौजवान पाकिस्तानी कैंपों में हथियारों, तोड़फोड़ और गुरिल्ला तकनीक के प्रशिक्षण हेतु भेजे जा रहे हैं और जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें लुका-छिपाकर वापस लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शुरू में तीन प्रशिक्षण कैंप थे, जिनमें से दो पाक अधिकृत कश्मीर में तथा तीसरा पाकिस्तान में था। यह भी खबर है कि प्रशिक्षण हेतु ६० लाख रुपए का बजट रखा गया था। बाद में इसमें ४० लाख रुपए और बढ़ाये गये। नतीजतन इस मद पर

कलाश्नीकोव का मुकाबला डंडों और पुरानी राइफलों से

खर्च एक करोड़ तक पहुंच गया। इन कैंपों में घातक हथियारों का इस्तेमाल तो सिखाया ही जाता है, साथ में युद्धरत मुजाहिदों की फिल्में भी दिखायी जाती हैं। तीन सप्ताह के प्रशिक्षण में दो सप्ताह पाकपरस्त जेहन बनाने में गुजारा जाता है।

आतंकवादियों की आमद : सूत्रों का कहना है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कश्मीरी नौजवानों का पहला दस्ता मई '८८ में किसी तरह कश्मीर पहुंचा। कश्मीरी दहशतपसंदों के प्रवेश की भनक भारतीय खुफिया को मिल गयी थी तथा खुफिया विभाग खोजबीन में जुट भी गया था। लेकिन जैसा कि अकसर होता है, गुप्तचर अभी छानबीन में लगे थे कि ३० जुलाई की रात में दो धमाकों की आवाज घाटी में गूंज गयी। दहशतपसंदों ने सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस और ९३ वर्ष पुराने श्रीनगर क्लब को अपना निशाना बनाया था। धमाकों के चंद घंटों के बाद ही भोर में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप लूट लिया गया था। उसके बाद से धमाके कश्मीर घाटी के लिए आम बात हो गयी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आजम इंकलाबी और नजीर अहमद अभी भी पाकिस्तानी कब्जेवाले कश्मीर में हैं और प्रशिक्षण कैंपों में काम कर रहे हैं। हालांकि बेनजीर भट्टो के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रशिक्षण केंद्रों के बंद होने की बात हुई थी, किंतु सूत्रों का कहना है कि कैंप अस्थायी रूप से बंद किये गये थे जो फिर से अन्य जगहों पर खुल गये हैं। हाल में अपने एक साक्षात्कार में भी शब्बीर ने इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान की जानकारी में प्रशिक्षण केंद्र चलाये जा रहे हैं। इत्तफाक की बात है कि यही शब्बीर अनंतनाग में लिबरेशन फ्रंट के आपरेशन का एरिया कमांडर भी है।

चूंकि योजना थी १३ जुलाई, १९९० को विस्फोट करने की और भांडा समय से पहले ही फूट गया, इसलिए अब रणनीति बदलने की कोशिश की जा रही है। अब लूटपाट, हिंसा, आगजनी और बम के धमाकों में तेजी सिर्फ इसलिए लायी जा रही है, ताकि न्याय-व्यवस्था तंत्र का मनोबल गिराया जा सके और प्रचार पाया जा सके।

हाल की आतंकवादी गतिविधियों में एक खास बात यह उभर कर सामने आयी है कि दहशतपसंद ऐसी जगहों पर हिंसक गतिविधियां शुरू करते हैं, जहां कम-से-कम जानी नुकसान हो। मसलन, गत दिनों सिनेमा हाल में बम विस्फोट ऐन उस समय हुआ, जब रात का शो देखकर लोग हाल से बाहर जा चुके थे। इसी तरह गेलार्ड होटल पर उस समय हमला किया गया, जब वह खाली था। आम तौर से खाली बसों तथा गाड़ियों को ही दहशतपसंद अपना निशाना बनाते हैं। बादशाह चौक ही एक ऐसी मिसाल है, जहां के विस्फोट में सात लोगों की जानें गयीं। दहशतपसंदों ने जानी नुकसान न करने की रणनीति शायद इसीलिए तैयार की है, क्योंकि वे कश्मीरी जनता की सहानुभूति नहीं खोना चाहते।

आतंकवादियों की संख्या : सरकारी आंकड़ों के अनुसार कश्मीर घाटी में ३०० प्रशिक्षित दहशतपसंद मौजूद हैं, जिनमें से १०० को गिरफ्तार

साक्षात्कार/**नियाज ए नायक**

हिंदुस्तान में पाकिस्तान-कार्ड का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है

"मैं हिंदुस्तान में रहकर बिलकुल अपने वतन-सा अहसास करता हूं," कहनेवाले भारत में पाकिस्तान के राजदूत नियाज ए नायक कामकाज में जितने फुर्तीले हैं, उतने ही हाजिरजवाब भी। 'माया' ने आतंकवादियों को पाकिस्तानी प्रशिक्षण और मदद जैसे नाज़ुक विषय पर उनसे बहुत खुलकर बातचीत की तथा उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ सवालों का नपा-तुला जवाब दिया। प्रस्तुत हैं, बातचीत के प्रमुख अंश :

***माया :** पंजाब और कश्मीर भारत-पाक संबंधों में सदा कांटे की तरह चुभते रहे हैं। फिर पाकिस्तान पर तो यह भी आरोप है कि वह आतंकवादियों को प्रशिक्षण तथा सहयोग देता है। हाल में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी ने आपसी संबंध मधुर बनाने के जो प्रयास किये हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए क्या यह माना जा सकता है कि उपर्युक्त बातें हो सकता है कभी सही रही हों, किंतु अब इस तरह के इलजाम बेबुनियाद हैं?*

नियाज ए नायक : मैं अगर यह कहूं कि यह सब गुजरे जमाने की बातें हैं और अब ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि पहले कभी पाकिस्तान दहशतपसंदों की या खालिस्तानी अनासिर (खालिस्तान समर्थक) की मदद करता था। जबकि यह सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। मैं ऐसी बेबुनियाद बातों पर तवज्जो नहीं देता। मैं पाकिस्तानी सरकार के हमेशा करीब रहा हूं और मैं इस बात से खूब वाकिफ हूं कि पाकिस्तान जैसा छोटा-सा मुल्क कभी ऐसा सोचता भी नहीं कि वह हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे, चाहे मसला कश्मीर का हो या पंजाब का।

माया : अतींदर पाल सिंह, जिस पर श्रीमती गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है, के लिए अभियोग पत्र में यह बताया गया है कि उसे पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया और उसे पाकिस्तान ने हथियार भी दिये जिसमें एफ-४७ बंदूकें शामिल थीं। ताज्जुब है कि इस लिखित आरोप पर आपकी सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी सरकार आंतकवादियों की मदद कर रही है या अफगान मुजाहिदीन?

नायक : जहां हथियारों की जरूरत होगी वहां हथियार किसी-न-किसी जरिये पहुंच ही जायेंगे। दहशतपसंदों को हथियार कौन देता है, पाकिस्तान, पाकिस्तानी लोग या अफगान मुजाहिदीन, यह एक टेढ़ा सवाल है। जहां तक अफगान मुजाहिदीनों पर शक की गुंजाइश है, उसका खात्मा तो सिर्फ इस हकीकत से हो जाता है कि मुजाहिदीन को खुद इतने हथियारों की जरूरत है कि वे दूसरों को क्या देंगे? रही बात पाकिस्तान की शह और मदद की, तो मैं सिर्फ यह कहना बेहतर समझता हूं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान-कार्ड का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सियासत में कभी-कभी किसी हद तक ऐसे मुद्दों को उछालकर फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हद से बाहर नहीं।

माया : कुछ भी हो, आतंकवादी बिना रोक-टोक बार्डर से आ-जा रहे हैं और उनके लिए हथियार भी पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। क्या आपकी सरकार आतंकवादियों की आमद-रफ्त और हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए कोशिश करेगी?

नायक : दोनों मुल्कों ने बार्डर से आने-जाने पर सख्ती से रोक लगाने का फैसला किया है। मुझे

किया जा चुका है। अन्य सूत्रों से जांच-पड़ताल करने पर भी यही संख्या सामने आती है। ऐसे में ९९.५ प्रतिशत मुस्लिम आबादीवाले कश्मीर को मात्र ३०० पाकिस्तानी समर्थकों के कारण पाकिस्तान समर्थक कहना क्या उचित होगा? चिंता का विषय यह है कि ये चंद उग्रवादी नौजवान उन कुंठित युवकों की सहानुभूति पा रहे हैं, जिनकी तादाद काफी है। खासतौर से उन लाखों बेरोजगार युवकों की जो रोजगार की तलाश में कश्मीर की सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं।

राज्य में बेरोजगारी दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है, जिससे असंतोष और गुंडागर्दी का वातावरण पनप रहा है। राज्य के मुख्य सचिव मूसा रजा भी बेरोजगारी से उपजी विषम स्थिति से इनकार नहीं करते। मूसा रजा बताते हैं कि जब सरकार ने ४५०० अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन किया था, तो १.६५ लाख प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। यही नहीं, इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक दरकार थी, लेकिन जिन लोगों ने आवेदन किया था, उनमें पीएच-डी, एमए, बीए आवेदकों की भरमार थी। ऐसी स्थिति में प्रशासन बेबस हो जाता है। जाहिर है प्रशासन के प्रति उन युवकों में असंतोष पनपता है जो बड़ी-बड़ी डिग्रियों के बावजूद स्थान न होने के कारण नियुक्त नहीं हो पाते। कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करते हुए मूसा कहते हैं, "जो नौजवान पाकिस्तान प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, वे उस भीड़ में से तो नहीं जो बेरोजगारी से आजिज हैं। पाकिस्तान जानेवाले वे लोग हैं, जिनके दिमाग जमात ने बदले हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बेरोजगारों की हमदर्दी मिल जाती है। बेरोजगारों की नजर में उग्रवादी हीरो हो जाते हैं।"

फारूक से खफा: मौलाना फारूक

फारूक के प्रति रोष: बेरोजगारी तो जो है सो है, कश्मीर की इससे भी बड़ी समस्या है फारूक अब्दुल्ला के प्रति बढ़ता असंतोष। क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि किसी भी क्षेत्र में सही काम नहीं हो पा रहा है। विद्युत आपूर्ति ही ले लीजिए। स्थिति यह है कि सप्ताह के मात्र ६ दिनों में प्रतिदिन तीन घंटे ही विद्युत आपूर्ति हो पा रही है। कल्पना की जा सकती है कि जहां ठंड कड़ाके की पड़ती है, वहां बिना बिजली के आम आदमी कैसे गुजर-बसर कर रहा होगा? श्रीनगर की एक बस्ती में रहनेवाला मुश्ताक इस संबंध में कहता है, "बिजली की खराब हालत से निबटना आसान नहीं। महीने में मिलनेवाली प्रति व्यक्ति २० सेर लकड़ी से कैसे सर्दी काटी जा सकती है? मुश्ताक जैसे-तैसे अपने परिवार के चार सदस्यों का पेट पालता है, "पहले कुछ सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब तो यह मजाक लगती है।" मुश्ताक कहता है।

शब्बीर शाह

आजम इंकलाबी

भ्रष्टाचार का शिकंजा: भ्रष्टाचार दीमक की तरह कश्मीर की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सड़क पर आने भर की देर है। चौराहे-चौराहे तरह-तरह की कहानियां सुनने को मिल जायेंगी। स्थिति यह है कि पूर्व मुख्य सचिव जिस फार्म के मालिक हैं, वह सरकार में ईमानदारी से काम करके खरीदा ही नहीं जा सकता। यही नहीं, श्रीनगर निवासी सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के एक अभियंता ने देखते-ही-देखते ४० लाख रुपए की जमीन खरीद ली और उस पर जाफरान (केसर) का बाग लगवा दिया। क्या एक मामूली अभियंता के लिए यह संभव है?

उम्मीद है कि इस्लामाबाद की बैठक में इस मसले पर खास ध्यान दिया जायेगा।

माया: हम इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भारत से संबंध मधुर बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा गुट है जो बेनजीर भुट्टो की नजर से बच-बचा कर आतंकवादियों की मदद कर रहा है?

नायक: मैं किसी ऐसे गुट या गिरोह को नहीं जानता।

माया: हाल में समाचारपत्रों में कुछ ऐसे चित्र प्रकाशित हुए हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि आतंकवादियों को पाकिस्तानी इलाके में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यदि वे चित्र पाकिस्तानी इलाके के नहीं, जैसा कि आपका दावा है, तो आपकी सरकार प्रतिक्रिया क्यों नहीं करती?

नायक: ऐसे दस्तावेजों पर चुप रहना ही ज्यादा बेहतर है। बेवजह बेसिर-पैर की बातों को लेकर बात का बतंगड़ बनाना बेहतर नहीं। सीधी-सी बात है कि अगर पाकिस्तान में वाकई दहशतपसंद तालीम (प्रशिक्षण) पा रहे हैं, तो क्या उनकी तस्वीर आसानी से ली जा सकती है या किसी को इस बात की इजाजत हो सकती है? फिर जिस तरह की तस्वीरें प्रकाशित हुई हैं उन्हें तो कोई भी कैमरे की मदद से हिंदुस्तान में तैयार कर सकता है। बस दो सिखों की जरूरत है। उनको हथियार थमा दीजिए और तस्वीर खींच लीजिए।

माया: तो फिर आपकी सरकार चित्र का विरोध क्यों नहीं करती?

नायक: अगर मौजूदा माहौल में हमारी हुकूमत इन मामूली-मामूली बातों के इकरार और इनकार के झमेले में फंस जायेगी, तो दोनों मुल्कों के बीच खुशगवार ताल्लुकात की जो हवा बहनी शुरू हुई है वह फिर थम जायेगी। मैं समझता हूं कि दोनों हुकूमतें असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

माया: अतींद्र पाल सिंह ने अपने बयान में पंजाब में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की बात कही है। आपकी सरकार उसकी इस बात पर भी क्यों चुप्पी साधे है?

नायक: सचाई तो यह है कि जब मैंने अखबारों में दूसरी चार्जशीट के बारे में पढ़ा और इस बात से वाकिफ हुआ कि अतींदर पाल पर क्या इलजाम हैं, तो मैं इलजाम की असलियत समझ गया। मैंने इस मामले को अपनी सरकार तक पहुंचाया भी नहीं।

माया: डाक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने पचास ऐसे आतंकवादियों को गिरफ्तार कर रखा है जिन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया। डा० अब्दुल्ला के इस इलजाम पर आप क्या कहना चाहेंगे?

नायक: लगता है अपनी कमी और कमजोरी को ढांकने के लिए फारूक हमारे सर इलजाम मढ़ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में पाकिस्तान पसंद जेहनियत आज भी कारफरमा है, लेकिन यह भी सच है कि हुकूमते पाकिस्तान इस जेहनियत का नाजायज फायदा नहीं उठाती।

माया: क्या भारत-पाक संबंधों में कांटे की तरह चुभ रहे तीन लड़ाइयों के इतिहास को दरगुजर करके संबंध मधुर बनाये जा सकते हैं?

नायक: ताल्लुकात बिलकुल बेहतर बनाये जा सकते हैं। हाल में हिंदुस्तान के वजीरेआजम का सार्क बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाना और दोनों वजीरेआजम के बीच रिश्ते बेहतर बनाने की बातचीत होना इस बात का खुला ऐलान है। मुझे यकीन है कि जब दोनों वजीरेआजम ने बेहतर रिश्तों की बात शुरू की, तो उनके मन में जंगों की तारीख नहीं थी। गुजरे हुए हादसात को भुलाकर दोस्ती के लिए नयी पहल शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है आनेवाला जमाना आज से बहुत बेहतर होगा।

यही नहीं, बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक वरिष्ठ अभियंता को घोटाले के कारण संकट में फंसना पड़ा था। एक अधिशासी अभियंता घूस की कमाई से अपने बेनामी धंधों को सींच रहा है। इस तरह से बड़ी लंबी सूची है सिर्फ यह बताने के लिए कि राज्य में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? जब 'माया' ने एक आयकर अधिकारी से उपर्युक्त तथ्यों की रोशनी में सवाल किया, तो उनका सीधा जवाब था कि इस तरह की जांच-पड़ताल करने का उनको अधिकार नहीं।

भ्रष्टाचार से संबंधित एक और मिसाल देना बहुत जरूरी है। १९८३ में एक आदेश के जरिये लोहे की चादरों के सामान को बिक्रीकर से मुक्त कर दिया गया था और नालीदार चादरों पर से बिक्रीकर नहीं हटाया गया था। किंतु ताज्जुब इस बात पर है कि आयकर विभाग में नालीदार चादरों की कर अदायगी का अता-पता नहीं है, जबकि कश्मीर में आज भी करोड़ों रुपए की चादरें मौजूद हैं। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ नालीदार चादरों में ही २० करोड़ रुपए के बिक्रीकर की चोरी हुई है। जबकि बिक्रीकर विभाग १९८३ के बाद नालीदार चादरों के अस्तित्व से ही इनकार करता है। क्या २० करोड़ रुपए की चोरी बिक्रीकर विभाग के तालमेल से नहीं हुई?

केंद्र का कर्जा: नतीजतन राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिन-पर-दिन केंद्र के कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। गत वर्ष मार्च के अंत तक राज्य द्वारा केंद्र को कुल देय कर्ज १७०९.०२ करोड़ रुपए था। इस साल स्थिति यह है कि राज्य को कुल मूल के रूप में ही ७८७९.४३ लाख रुपए अदा करने हैं जिस पर कुल ब्याज १५२७२.७७ लाख रुपए होते हैं। यदि इस वर्ष मूल कर्ज की अदायगी नहीं हुई, जो असंभव है, तो अगले वर्ष राज्य को केवल ब्याज के रूप में ही १६१.५८ करोड़ रुपए केंद्र को देने होंगे। नतीजतन उसे अगले वित्तीय वर्ष में कुल ११२८.७७ करोड़ केंद्र से मिलेंगे, जिनमें ४०८.९१ करोड़ रुपए योजनागत एवं गैरयोजना गत ऋण के रूप में शामिल होंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष (८९-९०) में केंद्र ने कश्मीर को ५२९.२१ करोड़ रुपए की राशि दी, जिसमें ३३५.०५ करोड़ कर्ज था और बाकी अनुदान। इसके बावजूद १०३.८४ करोड़ रुपए बजट घाटा पूरा करने के लिए चाहिए, जिसकी केंद्र से बातचीत चल रही है।

यही नहीं, आठवें वित्तीय आयोग ने भारतीय संविधान की धारा २७५ के तहत कश्मीर के लिए अनुदान के रूप में ५९६ करोड़ रुपए निर्धारित किये थे, जबकि इस बीच कश्मीर पर सिर्फ कर्ज ही ६०० करोड़ रुपए था। इससे भी बढ़कर आश्चर्य में डालनेवाला तथ्य यह है कि सातवीं योजना के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए भी लगभग ४३८ करोड़ रुपयों की जरूरत थी।

मृतक गुलाम मोहम्मद शाह (दायें) का परिवार

पर्यटन की हालत: जब बात कश्मीर की आर्थिक स्थिति पर ही चल पड़ी है, तो यहां पर कश्मीर के प्रमुख उद्योग 'पर्यटन' की स्थिति का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करना जरूरी है। कौन नहीं जानता कि कश्मीर सरकार की आय का प्रमुख साधन ही पर्यटन उद्योग है? कश्मीर की हिंसक घटनाओं और फारूक अब्दुल्ला के 'श्रीनगर की सड़कों पर युद्ध छेड़ने के ऐलान' ने पर्यटकों को कश्मीर से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हर साल बड़ी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र से पर्यटक कश्मीर पहुंचते थे, किंतु इस बार अप्रैल के अंत तक सन्नाटा छाया रहा। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एमवाई खान बताते हैं, "सच तो यह है कि मात्र पर्यटन उद्योग के सहारे लगभग ४०० करोड़ रुपए सालाना का कारोबार होता है। गत वर्ष अप्रैल के महीने में ५७,००० पर्यटक कश्मीर घूमने आये थे, जबकि इस साल पर्यटकों की संख्या में ६० प्रतिशत की कमी देखी जा रही है।" प्रबंध निदेशक की चिंता तो एक तरफ रही, कश्मीर निवासी मोहम्मद कोका जिसके पास चार टैक्सियां हैं, (जिनमें से तीन ऋण पर खरीदी गयी हैं) पर्यटकों की कम संख्या देखकर काफी निराश है। उसने 'माया' से कहा, "साहब! सच तो यह है कि अगर सैलानी इसी तरह कश्मीर से नजरें फेरे रहते हैं, तो कश्मीर के भिखारी तक भूखे मर जायेंगे। कश्मीर में लगभग १५०० टैक्सियां हैं जो यदि सैलानी खासी तादाद में आये होते, तो हर रोज कम-से-कम ३०० रुपए कमाते, किंतु सैलानियों के न आने से ज्यादातर टैक्सियां बेकार खड़ी हैं। ऐसे में कर्ज की अदायगी का सवाल ही नहीं पैदा होता।" यही नहीं कश्मीर बुकशाप के काउंटर पर बैठें अब्दुल रशीद भी मंदी की बात करते हैं और शाकाहारी भोजनालय के एमएल कौल भी व्यापार में घाटे की शिकायत करते हैं। सबके सामने समस्या बस पर्यटकों का न आना है। स्थिति तो यह है कि हाउसबोट मालिकों के संगठन के अध्यक्ष गुलाम रसूल पीर भी पर्यटकों की नजरें फिर जाने से काफी परेशान हैं। वे कहते हैं, "हाउसबोट का धंधा तो इस साल चौपट नजर आता है। सिर्फ डीलक्स क्लास के उन हाउसबोटों को ही फायदा होने का इमकान है, जिनको बड़ी एजेंसियों ने पूरे सीजन के लिए बुक कर रखा है। बाकी हाउसबोटों के लिए तो अब तक रोने-पीटने का ही माहौल बना है।" जूतों पर पालिश करनेवाला मोहम्मद हुसैन अली कश्मीर की मौजूदा स्थिति से काफी डरा हुआ है। उसे तो हालत सुधरने की उम्मीद ही नहीं है। यही नहीं राजीव गांधी के एक पुराने मित्र तथा कश्मीर में होटल व्यवसाय के अग्रणी विजय धर भी कश्मीर के बिगड़ते हालात से चिंतित हैं। वे बताते हैं, "पर्यटन उद्योग का तो जो हश्र हो रहा है, सबके सामने है। अफसोस तो इस बात का है कि इस उद्योग में आयी मंदी का संपूर्ण आर्थिक स्थिति पर असर होगा। किया भी क्या जा सकता है? हालत यह है कि कश्मीर हमेशा दिल्ली की तरफ हाथ फैलाये रहता है और दिल्ली अब तक उसकी मदद करती आयी है।"

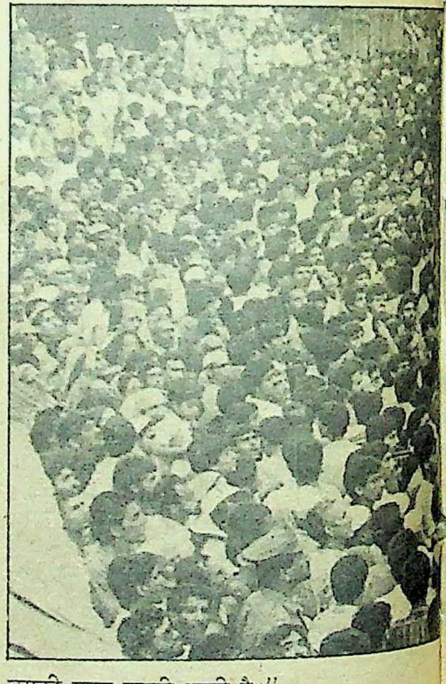

धार्मिक कट्टरता में तेजी: मजे की बात तो यह है कि जहां कश्मीर घाटी में पर्यटन दम तोड़ रहा है, वहीं धार्मिक कट्टरता ने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं। रीगल चौक स्थित अनारकली रेस्त्रां में एक अजीबोगरीब सूचना टंगी दिखी जिसमें लिखा है "अफतार के समय (७ बजे शाम) से पहले मुसलमानों की सेवा नहीं की जायेगी।" यही नहीं, श्रीनगर की सभी शराब की दुकानें ६ बजे शाम को बंद हो जाती हैं। यह सब सिर्फ इसलिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कट्टरपंथियों ने रमजान के महीने को बहाना बनाकर दुकानदारों को ऐसा करने की धमकियां दे रखी थीं। हद तो यह है कि शुरू में

कट्टरपंथी चाहते थे कि रमजान के महीने भर शराब की दुकानें खुलें ही नहीं, किंतु बाद में ६ बजे शाम को दुकान बंद करने का समझौता हो गया। आमतौर से दुकानें ९ बजे रात तक खुली रहती हैं। संयोग से फुटकर शराब बेचने के कारोबार का बड़ा हिस्सा हिंदुओं के हाथ में है। घाटी में बढ़ती कट्टरता को मद्देनजर रखते हुए बहुतेरों ने शराब का धंधा छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। यही नहीं, हाल में शराब की दुकानों की लूटपाट की घटनाएं तो सामने आयीं ही, साथ में ऐसा भी देखा गया कि एक ही मालिक की विभिन्न शराब की गुमटियों को लूटपाट का निशाना बनाया गया। जबकि गैरलाइसेंसी शराब की दुकानों पर आज भी बड़गाम में दुगुनी कीमत पर देर रात गये धड़ल्ले से शराब बिकती है। इसी तरह कारानगर से लेकर श्रीनगर के बीच स्थित दुकानों पर भी शराब रात में उपलब्ध रहती है, जबकि इस क्षेत्र को कट्टरपंथियों का गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि अनंतनाग में शराब की तीन दुकानें थीं, जिन्हें जोर जबर्दस्ती करके आठ साल पहले बंद करा दिया गया था। किंतु आज भी अनंतनाग में शराब हासिल करना मुश्किल बात नहीं है। असल में अब लाइसेंसधारी विक्रेता (जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं) शराब का स्टाक कुछ विशेष लोगों के हाथ सुपुर्द कर देते हैं जो मनचाही कीमत पर शराब उपलब्ध कराते हैं। सोपोर की तो यह स्थिति है कि वहां शराब की कोई दुकान न होने के बावजूद वहां शराब आसानी से मिल जाती है।

फारूक के खिलाफ माहौल : कट्टरपंथियों की सभा

धर्मनिरपेक्षता को लीलती सांप्रदायिकता : पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी में कट्टरता ऐसी बढ़ी है कि कश्मीर में उद्योग-व्यापार कर रहे अल्पसंख्यकों को आये दिन धमकी मिलना आम बात हो गयी है। 'माया' ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया, तो उन्होंने धमकियों की बात स्वीकार तो की, किंतु विस्तृत जानकारी देने से मुंह फेर लिया, क्योंकि उन्हें डर है कि कट्टरपंथियों को अगर पता चल गया, तो लेने के देने पड़ जायेंगे। हालांकि कश्मीर के पुराने लोग आज भी इस बात को दोहराते देर नहीं करते कि वास्तव में अधिकांश कश्मीरी स्वभाव और परंपरा से धर्मनिरपेक्ष हैं, किंतु धीरे-धीरे स्थितियां बदलती जा रही हैं। हालात तो यह है कि यदि कश्मीर में कोई हिंदू अन्याय की गुहार करता है, तो सांप्रदायिक कहलाता है और यदि कोई मुसलमान बेइंसाफी की शिकायत करता है, तो पाक समर्थक हो जाता है।

यही नहीं, कश्मीर घाटी के मशहूर फनकार बंसी परीमू इस बात पर जोर देते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोग ही हिंदू समुदाय के लोगों की देखभाल करते हैं। अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए तर्क के रूप में वे कहते हैं, "कश्मीर में हिंदुओं की आवादी कुल आबादी का .५ प्रतिशत ही है। ऐसे में यदि कश्मीरी मुसलमान धर्मनिरपेक्ष न हों, तो क्या हिंदुओं की कश्मीर में गुजर-बसर संभव है? असल में केंद्र ने गलती यह की है कि कश्मीर की कुरसी पर फारूक को बिठाकर उसने फारूक को तो खुश कर दिया, लेकिन कश्मीर के आम मुसलमानों को नाराज कर लिया। क्योंकि आम मुसलमान आज भी यह मानता है कि कश्मीर में साफ-सुथरे चुनाव न होने के कारण उनकी राय को अहमियत नहीं मिली। उनकी नाराजगी की शायद यही वजह है।" इस संबंध में मौलाना अब्बासी कहते हैं, "कश्मीर में ज्यादातर लोगों का मानना है कि जनता पार्टी के दौर को छोड़कर आज तक वहां साफ-सुथरे इंतखाब (चुनाव) नहीं हुए। हालांकि १९७७ में कश्मीर में जनता पार्टी इलेक्शन हार गयी और शेख अब्दुल्ला दोबारा गद्दीनशीं हुए, लेकिन आम आदमी को इस बात का अहसास तो हुआ कि कश्मीर में पहली बार साफ-सुथरे इंतखाब हुए।" कुछ इसी तरह का दृष्टिकोण पेश करते हुए काजी निसार कहते हैं, "कश्मीर में किसकी हुकूमत बनती है, किसकी नहीं, इससे हिंदुस्तान का क्या बनता-बिगड़ता है? फिर कश्मीर का भारत में विलय का मुद्दा तो तय हो चुका है। सचाई यह है कि कश्मीरी आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के साथ है। ऐसे में अगर जमाते-इस्लामी की हुकूमत बन जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर तमिलनाडु में डीएमके और आंध्र प्रदेश में तेलुगूदेशम हुकूमत बना सकती है, तो कश्मीर में अगर जमात की हुकूमत बनती है, तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर हुकूमते हिंद कश्मीर में अमन को क्यों नहीं पसंद करती?"

नौकरशाही का आलम : कश्मीर की आर्थिक स्थिति के बयान और घाटी में बढ़ती जा रही कट्टरता से कश्मीर की जो तस्वीर उभरती है वह तब और साफ हो जायेगी, जब घाटी के लिए प्रभावी और महत्वपूर्ण फैसले करनेवाली नौकरशाही का असली चेहरा सामने आयेगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि फारूक अब्दुल्ला की इच्छा भले ही कुछ हो, वास्तव में होता वही है, जो प्रशासन की बागडोर संभालनेवाले कुछ राजनीतिक रुझानवाले अधिकारी चाहते हैं। इनमें से कुछ ने तो फारूक अब्दुल्ला के अधीन रहकर अपनी छवि बनायी और कुछ ने जीएम शाह के जमाने में। सभी अफसरों का अलग-अलग रुझान है तथा हर समय घाटी की स्थिति गर्म बनाये रखने में उन्हें फायदा होता है।

साक्षात्कार/ फारूक अब्दुल्ला

हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन कश्मीर को जुदा नहीं होने देंगे

१९८३ के फारूक अब्दुल्ला और आज के फारूक अब्दुल्ला में काफी फर्क है। अगर यह कहा जाये कि बीच में सत्ताच्युत रहने पर जो अनुभव उन्हें हुए उनसे वे गंभीर हो गये हैं, तो अतिशयोक्ति न होगी। कश्मीर की मौज़ूदा उ़थल-पुथल ने उन्हें और संजीदा बना दिया है। आज उनकी पूरी कोशिश यही है कि वे किसी तरह दिल्ली को और पूरे राष्ट्र को इस बात का अहसास करा दें कि कश्मीर की उथल-पुथल में पाकिस्तान की घातक भूमिका है। 'माया' ने उनसे पाकिस्तानी हस्तक्षेप पर विस्तारपूर्वक बात की। बातचीत में यह साफ जाहिर हुआ कि वे देश की सुरक्षा और एकता के लिए काफी चिंतित हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं, ''कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन कश्मीर को अपने से जुदा नहीं होने देंगे।'' प्रस्तुत हैं, उनसे 'माया' की बातचीत के अंश :

माया : आखिर क्या वजह है कि बेनजीर भुट्टो के प्रधानमंत्री बनने पर शुरू के दिनों में आपने यह उम्मीद जाहिर की थी कि जल्द ही उपमहाद्वीप में शाति स्थापित होगी, लेकिन बाद में आपने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह हथियारबंद्र लोगों को कश्मीर में बदअमनी फैलाने के लिए भेज रहा है?

फारूक अब्दुल्ला : शुरू से मेरा खयाल यही रहा है कि अगर राजीव गांधी पाकिस्तान जाकर वजीरेआजम बेनजीर भुट्टो से दोस्ताना बातचीत करेंगे, तो दोनों मुल्कों के बीच अर्से से पनप रही दुश्मनी खतम हो जायेगी और दोनों मुल्कों की बहुत-सी परेशानियों का हल हो जायेगा। इस खयाल के तहत मैंने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत की तारीफ की थी और यह उम्मीद बांधी थी कि पाकिस्तान में दहशतपसंदों को ट्रेनिंग देने का जो काम हो रहा है वह बंद हो जायेगा। यही नहीं, मुझे तो पूरा यकीन था कि जिस दिन पाकिस्तान की मदद बंद हो जायेगी, शरपसंद अपने आप खामोश बैठ जायेंगे। लेकिन राजीव गांधी से बातचीत के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी दहशतपसंदों को पाकिस्तान में तालीम दी जा रही है। नतीजतन पाकिस्तान पहले की ही तरह आज भी दहशतपसंदों का अड्डा बना हुआ है। इसके अलावा कश्मीर के लिए पाकिस्तानी नजरिये में भी कुछ फर्क नहीं आया है। हालात पहले जैसे ही हैं। हर पाकिस्तानी अपनी तरह से कश्मीर पर अपना हक आज भी जता रहा है। यह कोई ढंकी-छिपी या राज की बात नहीं। बस मौका मिलने की देर है, सियासी सरबराहान भी कश्मीर पर पाकिस्तानी हक जताने से बाज नहीं आते। सोचने की बात है कि उनका नजरिया हमारे लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है? कश्मीर के बाशिंदे खरीद-फरोख्त का सामान नहीं कि जब जहां चाहा उठाकर रख दिया या जिसके हाथ चाहा बेच दिया। हमारी अपनी भी जिंदगी है, रहने का ढंग है, तौर-तरीका है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर का जर्रा-जर्रा हमारा है और हमको उससे मोहब्बत है। मैं बार-बार दुहरा चुका हूं कि कश्मीर हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन कश्मीर को अपने से जुदा नहीं होने देंगे। इस सच से पाकिस्तान इनकार करता है, तो करे। जब तक हमारे दम-में-दम है, हम कश्मीर की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान के इसी नजरिये से उसकी असल जेहनियत का अंदाज होता है। मैं पूछता हूं कि जब हिंदुस्तान दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है और पाकिस्तान भी दोस्ती की हामी भरता है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं? मतलब साफ है कि पाकिस्तान सचमुच हमारे मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बनाना चाहता। अगर उसका भी मंशा दोस्ती का होता, तो इस तरह की गैरजिम्मेदार बातें न उठती। सचाई यही है कि पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर पर इस्लामाबाद हावी है और उसी इलाके से उथल-पुथल की कार्यवाही की जाती है।

माया : लेकिन आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान हथियारबंद दहशतपसंदों को कश्मीर में उथल-पुथल पैदा करने के लिए भेजता है?

फारूक : बड़ी मामूली-सी बात है। बस समझने का फेर है। पाकिस्तानी कब्जेवाले कश्मीर का कामकाज देख रही हुकूमत के पास इतनी दौलत नहीं है कि वह मनमाने ढंग से खर्च उठाये और दूसरे मुल्कों में शरपसंदी बढ़ाने पर भी रुपए पानी की तरह बहाये। ऐसे में इस्लामाबाद के अलावा और कौन उसकी मदद करता होगा? फिर यह कोई नयी बात नहीं है। यह सिलसिला तो १९८३ से चला आ रहा है, जब मैं वजीरेआला था। १९८३ में कश्मीर में उथल-पुथल पैदा करने के मद में एक करोड़ रुपए रखे गये थे। जाहिर है, इतने सालों में इस मद में खर्च की जानेवाली रकम बढ़कर कई करोड़ हो गयी होगी। क्या यह मुमकिन है कि बिना इस्लामाबाद की मदद के इतना बड़ा खर्च उठाया जा सके? फिर चिदंबरम (गृहराज्य मंत्री) ने भी तो इस बात पर मुहर लगायी है कि कश्मीर की उथल-पुथल में पाकिस्तान का हाथ है।

माया : कहा जा रहा है कि हम अपनी कमजोरियों को ढांकने के लिए पाकिस्तानी दखल और पाकिस्तानी मदद की बात कर रहे हैं। आपका क्या खयाल है?

फारूक : ऐसा नहीं है। हम अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं, क्योंकि हमारी कमजोरी हमारे मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं पाकिस्तानी मदद की बात और पाकिस्तानी हाथ की बात सिर्फ अपनी कौम को इस बात से आगाह करने के लिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान आज भी कश्मीर में बदअमनी फैलाने का काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि मैं गलत नहीं कर रहा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। ऐसे में कौम को बेखबर रखना बेहतर नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी दखल पर पाबंदी लगाने और उसकी शरपसंदी पर लगाम लगाने के लिए पूरी कौम मेरे साथ आये, क्योंकि मैं तन्हा इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता।

माया : क्या आपने किसी ऐसे शरपसंद को गिरफ्तार किया है, जिसे पाकिस्तान में दहशतपसंदी की तालीम मिली हो? अगर हां, तो आप ऐसे लोगों की खुलेआम पैरेड क्यों नहीं कराते, जैसें पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान ने करायी थी?

फारूक : हमने ऐसे बहुत से लोगो को गिरफ्तार कर रखा है। उन लोगों के पास से जो कीमती और खतरनाक हथियार बरामद हुए, वे भी हमने राजीव गांधी को दिखाये हैं। अब हमने उन कैदियों को कश्मीर की जेल से हटाने का भी फैसला किया है। उन्हें कहीं दूसरे जेल में रखा जायेगा। क्योंकि इधर कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि कैदी आज भी किन्हीं जराये से राज की बातें अपने अड्डों तक पहुंचा रहे हैं।

माया : आपने अब तक ऐसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया है?

फारूक : करीब १००। हो सकता है इधर कुछ और

लोग गिरफ्तार हुए हों, इसलिए मैं यकीनी गिनती तो नहीं बता सकता। हाल में खुफिया ने यह खबर दी कि करीब १५० लोग छिप-छिपाकर कश्मीर में दाखिल हुए हैं।

माया: वैसे भारत सरकार पंजाब में तो गैरकानूनी ढंग से लोगों का प्रवेश नहीं बंद कर सकी है, क्या आप इस काम में कामयाब होंगे?

फारूक: जहां तक गैरकानूनी आमद-रफ्त का सवाल है, तो इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा पाना आसान बात नहीं है। जाहिर है, अभी १०० लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी सैकड़ों ऐसे शरपसंद बार्डर के उस पार इधर आने की कोशिश में जुटे होंगे। वैसे हम बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा अंदाज है कि करीब ३०० हथियारबंद लोग बार्डर के उस पार इधर आने की कोशिश में जुटे हैं और करीब ४०-५० शरपसंद कश्मीर में छिप-छिपाकर किसी तरह जिंदा है। हम उनकी तलाश कर रहे हैं।

माया: क्या आपने इस बात पर गौर किया कि कश्मीर मे उथल-पुथल ऐसे मौके पर शुरू हुई है, जब कश्मीर में टूरिस्टों का हुजूम आना शुरू होता है? जाहिर है, इससे हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा होगा?

फारूक: आप बिलकुल सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान का मंशा यही है कि वह हमारी सरकार की मआशी हालत (आर्थिक स्थिति) भी खराब कर दे। जाहिर है एक बार कश्मीर मआशी लिहाज से कमजोर हो जायेगा, तो कौमी नजरिया अपने आप कश्मीर के खिलाफ हो जायेगा। इसीलिए मैं बंबई जाना चाहता हूं, ताकि लोगों को पाकिस्तानी साजिश से आगाह करूं और उन्हें कश्मीर आने पर मजबूर करूं।

माया: लेकिन क्या टूरिस्टों के लिए कश्मीर महफूज जगह है?

फारूक: आप कश्मीर में हिफाजत की बात कर रहे हैं। कश्मीर की सैर करने आने वाला हर कौमी हुकूमते कश्मीर का खास मेहमान होता है। गुजिश्ता जाड़ों में एक जनवरी से १५ मार्च के बीच करीब ४८,००० टूरिस्ट कश्मीर घूमने आये थे और इस साल उथल-पुथल के बावजूद इस दौरान करीब ५५,००० टूरिस्ट कश्मीर घूम चुके हैं। इधर हालात कुछ ज्यादा खराब होने से लोगों में खौफ जरूर पैदा हुआ है। लेकिन आज भी हम उनकी हिफाजत और खुशगवार छुट्टी की जमानत लेते हैं।

माया: ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि शेख घराने का कश्मीर में दबदबा खतम हो रहा है, इसलिए कश्मीर पर हुकूमत मुश्किल हो रही है। आपका क्या खयाल है?

फारूक: ऐसा कुछ नहीं है। खुदा गवाह है कि कश्मीर में आज भी शेख घराने का पहले जैसा ही दबदबा है। मुमकिन है मेरे कांग्रेस से हाथ मिलाने पर कुछ बदगुमानी पैदा हुई हो। सच यह है कि मेरे और राजीव गांधी के बीच जो समझौता हुआ, वह वक्त की जरूरत थी। कश्मीर में पकड़ मजबूत कर रहा मजहबी जुनून पूरे मुल्क के लिए खतरनाक था, हिंदुस्तानी कौमियत के लिए खतरनाक था। उसी को दबाने, कुचलने के लिए, हमने हाथ मिलाया। मुझे फख्र है कि मैं मुल्क के काम आया। मेरा अपना खयाल है कि हमारी पार्टी, हमारे लोग और हमारी कौम मजहबी जुनून से ज्यादा बेशकीमती है। फारूक अब्दुल्ला को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन कौम और कौमी जजबे को नहीं। मेरा यकीन है कि हमारी फलाह (खैर) मिलकर रहने में ही है, टुकड़ों में बंटकर रहने में नहीं। हमें किसी खास मजहब या कौम की बात नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान एक मुल्क है, एक कौम है। हम जीयेंगे तो ८० करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ, मरेंगे तो उन्हीं ८० करोड़ की खातिर।

माया: आप कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद कैसा महसूस करते हैं जब आपके आसपास शेख साहब जैसे रुतबेवाला कोई सरबराह नजर नहीं आता?

फारूक: इस सवाल का जवाब भी एक सवाल है। मैं अगर यह पूछूं कि क्या इस वक्त हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल या बीसी राय जैसे सरबराह हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? गुजिश्ता सरबराहान का असर, उनकी शख्सीयत हमारे लिए मिसाल बन गयी है। हमारा उनसे मुकाबला करना बेहतर नहीं।

कश्मीर का जर्रा-जर्रा हमारा है और हमको उससे मोहब्बत है। मैं बार-बार दुहरा चुका हूं कि कश्मीर हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन कश्मीर को अपने से जुदा नहीं होने देंगे। इस सच से पाकिस्तान इनकार करता है, तो करे। जब तक हमारे दम-में-दम है, हम कश्मीर की हिफाजत करेंगे।

माया: आप पर इलजाम है कि आप ज्यादातर अपने सूबे से बाहर रहते हैं, इसीलिए कश्मीर में उथल-पुथल होती है?

फारूक: मेरे वालिद बुजुर्गवार कहा करते थे, "जिंदगी कशमकश का नाम है।" जाहिर है, अगर कोई इंसान जिंदगी की कशमकश का सामना करते हुए उस पर कामयाबी हासिल करता है, तो अफजल मखलूक (लौह पुरुष) होता है। इस तरह के इलजाम बेबुनियाद हैं। मैं भी एक मामूली आदमी हूं और जिंदगी की कशमकश से दो-चार हो रहा हूं। यह सरासर गलत बात है कि मैं सूबाई नज्म-जब्त (प्रशासनिक व्यवस्था) पर नजर नहीं रखता या बेखबर रहता हूं।

माया: कहा जाता है कि १९७५ का समझौता कश्मीरियों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने के लिए था। बाद में १९८७ का समझौता हुआ, लेकिन उसके लागू होने पर भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कश्मीरवासी राष्ट्रीय धारा से जुड़ गये हैं। जाहिर है, लोग उस वक्त तक लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक वे अपने आपको हिंदुस्तानी नहीं समझते। क्या आप लोगों में यह अहसास पनपा पाने में कामयाब हुए हैं?

फारूक: बेशक! मुझे फख्र है कि मैंने लोगों में हिंदुस्तानी होने का जजबा पैदा किया है। कश्मीर के बाशिंदों के लिए हिंदुस्तान ही सब कुछ है।

माया: इसमें शक नहीं कि आपके इस बयान का कि आप श्रीनगर की सड़कों पर पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं, पूरे मुल्क में बड़ा अच्छा असर हुआ। आपके इस बयान का कश्मीर में क्या असर हुआ?

फारूक: इसे खुशकिस्मती ही कहिए कि हालात ऐसे बने कि कश्मीर के बाशिंदों ने अपनी खुली आंखों से कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत की लड़ाई देखी। लड़ाई ऐसी कि यह बात भी वाजे हो गयी कि शरपसंदों को चंद कश्मीरी बाशिंदों की ही मदद हासिल है। इसलिए मेरे बयान का कश्मीर में क्या असर हुआ होगा, यह पूछना बेमानी है। हमारे सूबे की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिन सियासी सरबराहान के हाथों से हुकूमत छिनी है, वे आज भी हुकूमत हासिल करने के लिए तरह-तरह के सही-गलत रास्ते अपना रहे हैं। उनमें से कुछ तो मेरी ही पार्टी में हैं और कुछ कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे लोग नाजुक-से-नाजुक मसले का भी मजाक उड़ाते नहीं हिचकिचाते और उनकी कोशिश होती है कि हुकूमत के हर कदम को बदनाम किया जाये। बेरोजगारी से परेशान नौजवान भी ऐसे ही लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जाये, समझ में नहीं आता। इसके अलावा जब से मैंने राजीव गांधी से हाथ मिलाया, कुदरत भी कश्मीर का साथ नहीं दे रही है। अब तक कश्मीर न जाने कितनी बाढ़, बर्फीले तूफान और सूखे से नुकसान उठा चुका है। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। हाल में मुझे खबर मिली कि ३००० इंजीनियर काम से बिठा दिये गये हैं। हमें इंतजार है हुकूमते हिंद की मदद का, ताकि बेरोजगारी का हल किया जा सके।

माया: क्या आप यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हाथ मिलाकर आपने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, क्योंकि कट्टरपंथी आपके खून के प्यासे हो गये?

फारूक: मेरा यह मकसद कतई नहीं है। समझौता तो कश्मीर की खुशहाली के लिए हुआ है। मुझे यकीन है कि कश्मीर को खुशहाल बनाने में राजीव गांधी मदद करेंगे। यही बात तो मजहबी जुनून रखनेवालों को परेशान कर रही है। क्योंकि जिस दिन कश्मीर में खुशहाली कदम रखेगी, उनका सफाया हो जायेगा। इसीलिए पाकिस्तान मजहबी जुनून रखनेवाले अनासिरों की मदद कर रहा है। ताकि खुशहाली की रफ्तार धीमी पड़ जाये। ■

सूत्रों का कहना है कि स्थिति तो यह है कि कुछ सत्तासीन राजनीतिकों तथा कश्मीर के कुछ चालाक नौकरशाहों-दोनों ने ही विध्वंसकारी ताकतों से तालमेल बना रखा है, जिसका इस्तेमाल मौके-दर-मौके किया जाता है। इसकी परिणति यह हुई है कि ऐसी ताकतों ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तथा अब वे स्वयं स्वतंत्र रूप से सत्ता हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। इस संबंध में सूत्र डीआईजी वटाली की मिसाल पेश करते हैं, जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि उन्होंने सीमा के उस पार से कम आयु का एक ऐसा प्रमाण-पत्र हासिल किया, जिससे यह साबित किया जा सके कि उनकी नियुक्ति की फाइल में उनकी जो उम्र लिखी है, वह गलत है। इसके तहत उन्हें जून १९८७ में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था। उनके कुछ साथी भी इस बात का आरोप लगाते हैं कि कम आयु का प्रमाण-पत्र उन्होंने सीमा पार से हासिल किया है। यदि यह सही है, तो यह कैसे मान लिया जाये कि ऐसा अधिकारी सीमा पार से छिप-छिपाकर कश्मीर में दाखिल होनेवाले आतंकवादियों पर रोक लगायेगा?

बहरहाल, यह चेतावनी कि कश्मीर भारत के लिए पंजाब से ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होगा, काफी पुरानी हो चुकी है। असलियत तो यह है कि कश्मीर मसले का पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, कश्मीर के राजनीतिकों ने और नयी दिल्ली की सरकारों ने हमेशा अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आज कश्मीर में कोई ऐसा राजनीतिक नहीं बचा है, जिसकी नैतिकता पर संदेह न होता हो। यही नहीं, कश्मीर में भी कोई ऐसा नेता नहीं रह गया है, जिसको दिल्ली पर विश्वास हो, क्योंकि लगभग सभी मुख्यमंत्री-शेख अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद बख्शी, जीएम सादिक, मीर कासिम, फारूक अब्दुल्ला तथा जीएम शाह-दिल्ली की ही साजिशों के तहत ढाले जाते रहे हैं। नतीजतन आम कश्मीरी तो आज भी यह नहीं समझ पाता कि फलां व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बना और जब बन गया, तो फिर हटा क्यों दिया गया? शेख अब्दुल्ला को २२ साल तक जेल में रखकर वापस लाया गया था। इसी तरह फारूक को बिठाया गया और फिर टांग खींच ली गयी तथा बाद में फिर एक बार उन्हें गद्दीनशीं किया गया। यही नहीं, जीएम शाह को तो फारूक के खिलाफ तीन श्वेत-पत्र जारी करने तक की शह दी गयी। फिर शाह को सत्तानशीं किया गया और बाद में राष्ट्रविरोधी और सांप्रदायिक कहकर उठा फेंका गया।

फिलहाल कश्मीर की जो हालत है, उसके चलते फारूक अब्दुल्ला की जादुई छवि नेस्तनाबूद हो चुकी है। स्थिति यह है कि जो फारूक कश्मीर की वादियों में मोटर-साइकिल पर सवार होकर तफरीह करने निकलते थे, आज हथियारबंद दस्तों के साथ अपने सरकारी आवास से निकलते हैं। आज उन पर यह आरोप है कि जब घाटी में हिंसा और आगजनी का दौर चल रहा था, तो वे उधमपुर में गोल्फ खेल रहे थे।

फिर भी घुसपैठी आ रहे हैं: सीमा पर तैनात बल

IBRAHIM-SONS

आमने-सामने: पुलिस से मोर्चा लेते उग्रपंथी युवक

दूसरी ओर, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पड़ोसी देश से अच्छे संबंधों की बात करने के बावजूद उस कश्मीर कार्ड को फिलहाल अभी तक फेंक नहीं पायी हैं, जिसे उनके पहले के हुक्मरान पिछले ४० वर्षों से खेलते आ रहे हैं। यही नहीं, फारूक बावजूद स्थिति पर नियंत्रण करने की अपनी इच्छा के सारा इलजाम कट्टरपंथियों के सिर मढ़ कर भी अपने को बचा नहीं पा रहे। फिर नयी दिल्ली की घाटी की भारत-विरोधी भावना को उछालकर हिंदू मतों को हासिल करने की अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आयी है।

इसी पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के मरहूम राष्ट्रपति जिया-उल-हक ने पहले पंजाब, फिर कश्मीर और अंत में राजस्थान में आग लगाकर इस पूरे क्षेत्र को निगल लेने की योजना बनायी थी। आज पंजाब की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी नहीं और कश्मीर में जैसा हिंसक माहौल बन बिगड़ रहा है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। यह सही है कि जिया-उल-हक तो नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तानी सेना तो आज भी उसी नजरिये से सोचने पर मजबूर है। इस सोच को उसने अमली जामा पहनाना तेज कर दिया है। घुसपैठियों के जत्थे भेजकर उसने भारत पर जिस अघोषित युद्ध को छेड़ा है, उसकी परिणति को यदि किसी एक शब्द में कहा जा सकता है, तो वह है—भयानक।

◆

कश्मीरी पाकपरस्त नहीं हैं

अभी भी कश्मीर घाटी के बहुत से लोग कबायलियों के वेश में आये पाकिस्तानी हमलावर फौजियों के जूतों की उन आवाजों को नहीं भूले हैं जो ४२ साल पहले श्रीनगर की वीरान गलियों में गूंजी थीं। वे यह भी नहीं भूले हैं कि अपने उस कठिन समय में उन्होंने भारत से ही मदद मांगी थी और भारत सरकार ने उनके निवेदन पर तत्काल फौजें भेजी थीं। उन दिनों कश्मीर घाटी में अपने इलाके की सुरक्षा के लिए कश्मीरियों की राष्ट्रभक्ति का आलम यह था कि खुद बेगम अब्दुल्ला और डीपी धर की पत्नी ने औरतों की फौज तैयार करनी शुरू कर दी थी। इससे पाकिस्तान को गहरा झटका लगा था। ९४ प्रतिशत मुस्लिम आबादी के बावजूद कश्मीर घाटी के स्थानीय लोगों ने पाक हमलावरों की कोई मदद नहीं की थी। इसी कारण जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को यह विश्वास हो गया था कि यदि कश्मीर घाटी में जनमत संग्रह कराया जाये कि वे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या भारत के साथ, तो परिणाम भारत के पक्ष में होगा। यही वजह थी कि उस समय युद्ध विराम इसी वायदे पर हुआ था कि कश्मीर घाटी में जनमत संग्रह कराया जायेगा और यही वह मुद्दा है, जिसे बार-बार उछालकर पाकिस्तान व कश्मीर के कुछ पाकपरस्त लोग कश्मीर घाटी को अशांत करते रहते हैं।

दरअसल, यह तथ्य लोगों के दिमाग से उतर रहा है कि १९३३ में जवाहरलाल और शेख अब्दुल्ला की सूझबूझ ने कश्मीर घाटी से सांप्रदायिक उन्माद का सफाया कर दिया था। पंडित नेहरू ने ही शेख अब्दुल्ला से आग्रह किया था कि वे अपनी पार्टी 'मुस्लिम कांफ्रेंस' का नाम बदलकर 'नैशनल कांफ्रेंस' कर दें। पचास के दशक के प्रायः सभी जाने-माने कश्मीरी नेताओं ने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर की थी। इन नेताओं में वे गुलशाह (जीएमशाह) भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही यह कहा है कि शायद वे शीघ्र ही पाकिस्तानी झंडे की पोशाक पहनना शुरू कर दें। यही एक तथ्य यह संकेत देने के लिए काफी है कि किस तरह गुलशाह जैसे कुछ मौकापरस्त व असंतुष्ट लोगों की वजह से भारत के मैदानी इलाके के लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर के लोग पाकपरस्त हैं। ये ही कुछ लोग हैं जो हर साल पंद्रह अगस्त को कश्मीर घाटी के कुछ खास स्थानों पर पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं, भारत-विरोधी नारे लगाते हैं और उन सब मौकों पर सार्वजनिक रूप से खुशियों का इजहार करते हैं, जब भारत की किसी खेल स्पर्धा में पराजय होती है या उसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी किस्म का नुकसान होता है।

मौकापरस्ती: अब्दुल गनी खां लोन जब तक शेख अब्दुल्ला के साथ थे, तब तक भारत समर्थक थे, लेकिन जैसे ही वे शेख से अलग हुए, वैसे ही भारत-विरोधी हो गये और अब उन्हें लगता है कि अपनी पीपुल्स कांफ्रेंस पार्टी की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी है। वैसे लोन ने बार-बार दोहराया है कि भारत में कश्मीर का विलय एक सचाई है। कश्मीर में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो प्रमुखता पाने के लिए दूसरे नेताओं को पाकपरस्त साबित करते रहते हैं।

१९४७ में भारत की ५०० छोटी-बड़ी रियासतों के समान जम्मू-कश्मीर के सामने भी तीन विकल्प थे। या तो वह भारत में मिले या पाकिस्तान के साथ हो जाये अथवा स्वतंत्र रियासत बनी रहे। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का राजा इस रियासत का पाकिस्तान में विलय कर दे, लेकिन भारत जोर दे रहा था कि इस इलाके के भाग्य का फैसला करने का अधिकार सिर्फ यहां की जनता को है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी तब कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का नारा दिया था, जिसे शेख अब्दुल्ला की नैशनल कांफ्रेंस ने न केवल स्वीकार किया था, बल्कि गैरमुस्लिमों के लिए भी पार्टी के दरवाजे खोल दिये थे। इस बीच पाकिस्तान ने ताकत के बल पर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद कश्मीर ने विलय की प्रक्रिया के ही तहत जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये उसी से धारा-३७० का जन्म हुआ, जिसके अनुसार कश्मीर घाटी की सुरक्षा, विदेशी मामलों और संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर आया और शेष सभी मामले जम्मू-कश्मीर सरकार पर छोड़ दिये गये। तब कश्मीर की घाटियों में पहली बार नैशनल कांफ्रेंस के हल और तीन सितारों से युक्त लाल झण्डों के साथ-साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहराया था।

धर्मनिरपेक्षता की छवि: नेहरू

दरअसल यह तथ्य लोगों के दिमाग से उतर रहा है कि १९३३ में जवाहरलाल और शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी से सांप्रदायिक उन्माद का सफाया कर दिया था। पंडित नेहरू ने ही शेख अब्दुल्ला से आग्रह किया था कि वे अपनी पार्टी 'मुस्लिम कांफ्रेंस' का नाम बदलकर 'नैशनल कांफ्रेंस' कर दें।

कबायलियों के वेश में आये पाक फौजियों को पीछे हटा देने के बाद राजशाही की भी रवानगी हो गयी और प्रशासन की आपातकालीन देखभाल के लिए शेख अब्दुल्ला का कश्मीर की सत्ता पर आगमन हुआ। फलस्वरूप राजधानी भी जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित कर दी गयी। नैशनल कांफ्रेस ने डोगरा जमींदारों को बिना मुआवजा दिये जमींदारी प्रथा हटा दी। अधिकांश काश्तकर मुसलमान थे और जहां कश्मीर घाटी में उनकी संख्या अधिक थी, वहीं जम्मू में हिंदू बहुसंख्यक थे। इस कारण सांप्रदायिक आधार पर जम्मू और कश्मीर का अघोषित विभाजन हो गया। जम्मू से राजधानी के हट जाने से हिंदुओं ने खुद को आहत महसूस किया; तो शेख अब्दुल्ला की आपातकालीन सरकार का रवैया भी कमोबेश वैसा ही निरंकुश था जैसाकि राजशाही का था। इसका परिणाम यह हुआ कि नैशनल कांफ्रेंस के खिलाफ असंतोष जोर पकड़ने लगा और आहत हिंदू तथा लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष ताकतें नैशनल कांफ्रेंस की सरकार के खिलाफ एकजुट हो गयीं। शेख अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ चले आंदोलन की दो धाराएं थीं। एक धारा का नेतृत्व 'अखंड भारत' का नारा लगानेवाली प्रजा परिषद (बाद में जनसंघ) कर रही थी जो जम्मू-कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय चाहती थी, तो दूसरी धारा की रहनुमाई बलराज पुरी जैसे नेता कर रहे थे जो चाहते थे कि जम्मू को भी कश्मीर

घाटी की तरह पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो।

१९५२ में शेख अब्दुल्ला को पंडित नेहरू के साथ हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके द्वारा धारा-३७० के तहत जम्मू को भी स्वायत्तता प्राप्त हो गयी। इससे उत्साहित होकर प्रजा परिषद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए आंदोलन तेज कर दिया। दरअसल, शेख अब्दुल्ला यह मानकर चल रहे थे कि जम्मू-कश्मीर की अलग हैसियत है, जबकि शेष भारत के लोग यह मानते थे कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय हो चुका है। इसी आधार पर वे जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने के खिलाफ थे। उन्ही दिनों भारत सरकार द्वारा दिये गये इस वक्तव्य ने शेख अब्दुल्ला को कुपित कर दिया कि आंदोलन और उत्पात विलय का सही रास्ता नहीं है, इसे स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए। शेख अब्दुल्ला तब दहाड़े थे कि उन्होंने पाकिस्तान का गुलाम बनने से इनकार कर दिया था और वे कश्मीर को भारत का भी गुलाम नहीं बनने देंगे तथा इसके लिए संघर्ष करेंगे।

शेख अब्दुल्ला के इस लड़ाकू तेवर को शह देने के लिए कुछ विदेशी ताकतें तो जैसे इंतजार ही कर रही थीं। अमरीका ने केवल इस शर्त पर शेख अब्दुल्ला की सहायता करने की पेशकश की कि वे अपने इलाके से कम्युनिस्टों को खदेड़ दें, लेकिन शेख ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया था। ३ मई, १९५३ को अमरीकी नेता अदलाई स्टीवेंसन ने शेख से सात घंटों तक बातचीत की, जिसका हश्र यह हुआ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शेख को नैतिक समर्थन देना बंद कर दिया और एक अगस्त, १९५३ को एक प्रस्ताव पारित कर इस क्षेत्र में अमरीका द्वारा खेली जा रही कूटनीतिक चालों की भर्त्सना की।

शेख पर पाबंदी: शेख अब्दुल्ला पर आरोप लगा कि वे अमरीका के साथ साठगांठ कर रहे हैं। भारत सरकार की दृष्टि में वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक भारी खतरा बन चुके थे। फलस्वरूप उन्हें ९ अगस्त, १९५३ को गिरफ्तार कर लिया गया और वे १९७५ तक नजरबंद रहे, लेकिन कश्मीरियों के दिल में शेख गहरी जगह बना चुके थे। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। १९५७ में जम्मू-कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए और बख्शी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में वहां पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी और उन्हीं के शासन काल में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार सीमा को जम्मू-कश्मीर तक बढ़ा दिया गया। गुलाम मोहम्मद के बाद जीएम सादिक कांग्रेस के झंडे तले जम्मू-कश्मीर के सर्वेसर्वा बने। उनके काल में १९६४ में जम्मू-कश्मीर में कुछ संशोधनों के साथ संविधान की धारा ३५६ और ३५७ लागू की गयी, जिसके तहत यह प्रावधान था कि जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। इन धाराओं के लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर के 'प्रधानमंत्री' को 'मुख्यमंत्री' और 'सदर' (राष्ट्रपति) को 'राज्यपाल' कहा जाने लगा।

चंद लोग पाकपरस्त हैं: फारूक

शेख अब्दुल्ला ने नजरबंदी के दौरान इसका कड़ा विरोध किया और उनके आह्वान पर १९६५ में नैशनल कांफ्रेस ने कांग्रेसियों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कुछ कश्मीरी नेता मदद के लिए पाकिस्तान की ओर भी झुके। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इसी से उत्साहित होकर १९६५ में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, लेकिन जब पाक फौजों ने कश्मीर को अपना निशाना बनाया, तो आम कश्मीरियों ने इसका कड़ा विरोध किया। शेख अब्दुल्ला ने पाक हमले का विरोध नहीं किया, तो समर्थन भी नहीं किया। नैशनल कांफ्रेंस के जनमत संग्रह आंदोलन के महासचिव और शेख के दामाद गुल मोहम्मद शाह ने भी पाक हमले का समर्थन नहीं किया था। १९७१ के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार और बांग्लादेश के निर्माण से कश्मीर के उन लोगों के हौसले पस्त हो गये जो भारत-विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान से सहयोग की अपेक्षा रखते थे। दूसरी ओर, कश्मीरियों ने भी यह समझ लिया कि धर्म के बजाय क्षेत्रीय सभ्यता और संस्कृति राष्ट्रीयता का कहीं अधिक पुख्ता आधार है।

पट परिवर्तन: तब तक शेख अब्दुल्ला के सोच-विचार में भी काफी परिवर्तन आ चुका था। उन्होंने १९७५ में श्रीमती गांधी से हुए समझौते में इस सचाई को स्वीकार कर लिया कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत सरकार को भी यह महसूस हुआ कि सिर्फ शेख अब्दुल्ला ही कश्मीर के भारत-विरोधी और पाकपरस्त ताकतों पर अंकुश लगा सकते हैं। समझौते के तहत तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री मीर कासिम ने त्याग पत्र देकर शेख अब्दुल्ला के सत्तासीन होने का रास्ता साफ कर दिया। जनता पार्टी के शासनकाल मे १९७७ में जम्मू-कश्मीर में हुए चुनाव में यद्यपि जनता पार्टी हार गयी थी, लेकिन इससे पहली बार कश्मीरियों ने यह महसूस किया कि भारत देश के प्रति निष्ठा का मतलब जरूरी नहीं कि भारत सरकार के प्रति भी निष्ठा रखी जाये। पहली बार उन्होंने भारत राष्ट्र और भारत सरकार के बीच के फर्क को समझा और जो लोग राज्य सरकार के खिलाफ थे, उन्होंने उन चुनावों में भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया, लेकिन उन सब प्रत्याशियों का बिस्तरा गोल कर दिया जो पाकपरस्त थे। कश्मीर के इस बदले माहौल का ही नतीजा था कि जब शेख अबदुल्ला का निधन हुआ, तो उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया गया और उनके शव पर श्रद्धासुमन चढ़ानेवालों की पांत में न केवल तीन सौ सांसद खड़े थे, बल्कि खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी वहां उपस्थित थे।

शेख अब्दुल्ला के बाद उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने यद्यपि अपने पिता से भी अधिक मुखर शब्दों में जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया था, लेकिन विपक्ष की राष्ट्रीय धारा में आने की उनकी कोशिशों ने श्रीमती गांधी की सरकार को नाराज कर दिया। फलस्वरूप राजनीतिक चक्र उनके खिलाफ घूमने लगा। फारूक अब्दुल्ला को अपदस्थ होना पड़ा और दिल्ली के इशारे और शह पर उनके बहनोई गुल मोहम्मद शाह ने उनका स्थान ग्रहण किया, लेकिन वे अक्षम साबित हुए। उनके कार्यकाल में कश्मीर घाटी में राष्ट्रविरोधी उपद्रव भड़कने लगे और अंततः एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला को मसीहा घोषित करते हुए १९८७ में राजीव गांधी ने नैशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस-इ के गठजोड़ से बनी जम्मू-कश्मीर सरकार की बागडोर सौंप दी।

अपने पिता के समान फारूक को दूसरी बार जम्मू-कश्मीर की गद्दी जरूर मिली, लेकिन उनमें अपने पिता जैसा करिश्मा नहीं रहा। अब वे युवाओं के चहेते हीरो नहीं रहे और खुद प्रदेश कांग्रेस भी उन्हें पसंद नहीं करती। वे एक संदेहास्पद व्यक्ति बन चुके हैं और इसी माहौल में वे कश्मीर घाटी पर सरकार का नियंत्रण बरकरार रखने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जैसा कोई नेता नहीं है, जिसकी दहाड़ से कश्मीर घाटी में पनप रहे उपद्रव शांत हो जायें। लेकिन राहत की बात तो यही है कि अब वहां विलय-विरोध भी कोई मुद्दा नहीं है और न ही पाक प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो इस स्थिति में हैं कि भारत के खिलाफ कोई आक्रामक रवैया अपना सकें। इस समय कश्मीर में पाकिस्तान को मौकापरस्त और राष्ट्रविरोधी कुछ तत्वों द्वारा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल, पाकिस्तान अब वह स्थान नहीं रह गया है, जहां कश्मीरी अपने घर की तलाश कर सकें।

—विजय दत्त

साक्षात्कार : अरुण नेहरू

देश को कौन चला रहा है – सोनिया गांधी या सतीश शर्मा ?

राजनीति में दोस्ती ही नहीं, रक्त-संबंध तक स्थायी नहीं रह पाते। अरुण नेहरू और राजीव गांधी के संबंधों ने हाल में जो मोड़ लिया है, वह इसी बात का संकेत है। जो अरुण नेहरू सत्ता से निष्कासन के बावजूद राजीव गांधी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने से परहेज करते थे, अब उनके बारे में कटु-से-कटु बात कहने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। दूसरी ओर राजीव गांधी के वफादार अरुण नेहरू को विश्वासघाती, सरकारी गोपनीयता भंग करने का अपराधी और १९८४ के दंगे भड़काने का दोषी करार दे रहे हैं। चैक पिस्तौलों के कथित घोटाले के संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। लेकिन चैक पिस्तौलों के संबंध में पूछताछ करने आये सीबीआई के अधिकारियों को अरुण नेहरू ने ऐसी बातें बतायी हैं जो स्वयं राजीव गांधी और बूटा सिंह के लिए घातक हो सकती हैं। उन्होंने इटली के दिल्ली स्थित व्यवसाय-प्रतिनिधि क्वात्रोची की प्रधानमंत्री से घनिष्ठता पर प्रश्न उठाया है और बूटा सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जोर दिया था कि पिस्तौलें एक अन्य हथियार-व्यापारी के माध्यम से खरीदी जायें। घर के भेद खोलने पर तुले अरुण नेहरू से रंजना कक्कड़ ने लंबी बातचीत की है। अरुण नेहरू ने उनके हर सवाल का बेधड़क उत्तर दिया है और कहीं-कहीं राजीव गांधी और बूटा सिंह पर ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं, जिनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता। फिर भी उनकी उत्तेजक भाषा के छींटे यत्र-तत्र साक्षात्कार में बिखरे हैं। प्रस्तुत हैं, साक्षात्कार के अंश :

माया : *इस समय गृह मंत्री बूटा सिंह ने आपको ही आक्रमण के लिए क्यों चुना है?*

अरुण नेहरू : *गृहमंत्री नहीं प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री का तो कोई स्तर ही नहीं है। उसको तो मैं किसी गिनती में नहीं रखता। रही प्रधानमंत्री की बात, तो यह उनसे ही पूछिए।*

माया : *क्या वर्तमान हमले का कारण यह है कि आप सरकार के रहस्य जानते हैं?*

नेहरू : *सीधी बात यही है कि वे मुझसे घबराते हैं। वैसे एक तरफ तो यह कहते फिरते हैं कि मेरा कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, मुझे राजनीति की समझ नहीं। दूसरी ओर उनका पूरा समय मुझे घेरने में जाता है। यह तो मानव मनोविज्ञान है कि जिससे आदमी डरता है, उसी पर आक्रमण करता है।*

माया : *इस समय हमले का कारण क्या ठक्कर रिपोर्ट संबंधी आपकी जानकारी है?*

नेहरू : *सवाल मेरी जानकारी का नहीं, जनता की जानकारी का है। ठक्कर रिपोर्ट के संबंध में संसद में पहले दिन यही कहा गया कि इसको पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश टूट जायेगा और न जाने क्या-क्या आफतें आ जायेंगी। १५५ कांग्रेस सांसदों ने भी राष्ट्रहित की दुहाई दी। फिर पांचवें दिन प्रधानमंत्री ने सबको यह कहकर झूठा बना दिया कि इसमें कुछ है नहीं। सातवें दिन कह दिया कि ८००० पेजों में से कुल ६७० पेज ही देंगे। जो ७००० पेज छिपा रहे हैं, उनके संबंध में भारत के हर परिवार का एक ही सवाल है कि उसमें क्या-क्या छिपा रहे हैं? यही मैं भी पूछ रहा हूं।*

माया : *ठक्कर आयोग की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट के संबंध में आपकी क्या भूमिका थी?*

नेहरू : *किसकी क्या भूमिका थी, यह कार्रवाई सूची में स्पष्टतया लिखा है। ठक्कर का मुझसे कुछ लेना-देना नहीं था। मैं तो खुद सवाल कर रहा हूं कि ठक्कर को किसने नियुक्त किया? ठक्कर से कौन मिलता था? मैं तो सीधे-सीधे*

मप्र में माधव राव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, बन गये मोतीलाल वोरा। बिहार में तारिक अनवर को बनाना चाहते थे बन गये सत्येंद्र बाबू। राजस्थान में लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। दो महीने बाद देख लीजिएगा क्या होगा।

प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं। उनकी जवाबदेही है। वे चाहें तो मुझे गलत साबित कर दें। कह दें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं था और अरुण नेहरू देश चला रहे थे, तो मैं जिम्मेदारी मान लूंगा।

माया: आप सरकार चला रहे थे या नहीं, किंतु आम धारणा यही थी कि आप कम-से-कम प्रधानमंत्री का दायां हाथ अवश्य थे।

नेहरू: *सवाल दायें-बायें हाथ का नहीं। सवाल यह है कि वे प्रधानमंत्री थे या नहीं। नहीं हैं तो कह दें। आज देश को कौन चला रहा है? सोनिया गांधी चला रही हैं या सतीश शर्मा चला रहे हैं? सच बात यह है कि एक बार झूठ बोलो, तो सौ बार झूठ बोलना पड़ता है और जब कुछ छिपाना होता है, तो झूठ ही बोलना पड़ता है।*

माया: धवन को ठक्कर ने स्वयं दोषी पाया या किसी ने उनको गलत सूचनाएं देकर फंसवा दिया?

नेहरू: *आप राजीव गांधी से पूछ लीजिए या ठक्कर से पूछ लीजिए। सच्चाई यह है कि राजीव गांधी ही ठक्कर से बराबर संपर्क बनाये हुए थे। जब कहा जा रहा है कि ठक्कर के कान भरे गये हैं, तो यह काम वही कर सकता है जो उनके संपर्क में था।*

माया: कहा जाता है कि ठक्कर रिपोर्ट आपके पास काफी लंबे समय तक रही। रिपोर्ट का आंशिक भाग आपके पास था या पूरा?

नेहरू: *मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आप प्रधानमंत्री या गृहमंत्री से पूछें।*

माया: क्या पूरी रिपोर्ट पेश करने से सचमुच अंतरराष्ट्रीय क्षति पहुंचेगी?

नेहरू: *रिपोर्ट तो इनको (सरकार को) हरहाल पेश करनी ही पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय हित जैसी कोई चीज नहीं। मामला देश के प्रधानमंत्री की हत्या का है, जिसमे विदेशी हाथ की बात की जा रही है। ऐसे में उस विदेशी हाथ को बचाना चाहिए या उसको काट फेंकना चाहिए? मेरे विचार में तो प्रधानमंत्री को इसका पर्दाफाश करना चाहिए। यह तो अजीब बात है कि कोई देश हमारे प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचता है और हम उससे दोस्ती चाहते हैं। ऐसे देश से तो हमें राजनयिक संबंध ही तोड़ लेने चाहिए।*

माया: क्या रिपोर्ट गोपनीय रखने की सलाह प्रधानमंत्री को आपने दी थी?

नेहरू: *राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं या नहीं? वे अपनी अकल से काम करते हैं या दूसरों की। यदि वे कह दें कि उनमें अकल नहीं है, तो मैं बता दूंगा कि उन्हें किसने सलाह दी थी। आज वे जो निर्णय ले रहे हैं, वे अपनी अकल से ले रहे हैं या किसी और की अकल से।*

माया: आप राजीव गांधी की कार्यशैली से परिचित हैं। आपके हिसाब से वे किस प्रकार काम करते हैं?

नेहरू: *मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार ने सिर्फ उन्हीं छह महीनों में काम किया, जब मैं आतरिक सुरक्षामंत्री था। जब मैंने पद छोड़ा, तो पूरी सरकार ने काम करना बंद कर दिया। मुझे तो इंदिरा गांधी ने यही सिखाया था कि जो व्यक्ति हमेशा दोष दूसरों के माथे थोपने की कोशिश करता है, वह मात्र अपनी कमजोरी दिखाता है और यही जताता है कि उसमें हिम्मत नहीं। वह असुरक्षित और भयभीत है। ऐसे में परछाई को भूत समझ वह घबरा जाता है और यही आज हो रहा है।*

माया: कहा जाता है कि पहले राजीव गांधी की राजनीतिक शिक्षा-दीक्षा में और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में आपने महती भूमिका निभायी।

नेहरू: *(हंसते हुए) मैंने तो शायद हर काम में प्रमुख भूमिका निभायी है। आश्चर्य नहीं कल यह भी कह दिया जायेगा कि मैं भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार था। शीघ्र ही यह भी कहा जायेगा कि मैंने उनके बाल भी कटवाये, मुह भी धोया, दूध भी पिलाया। तथ्य यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया था।*

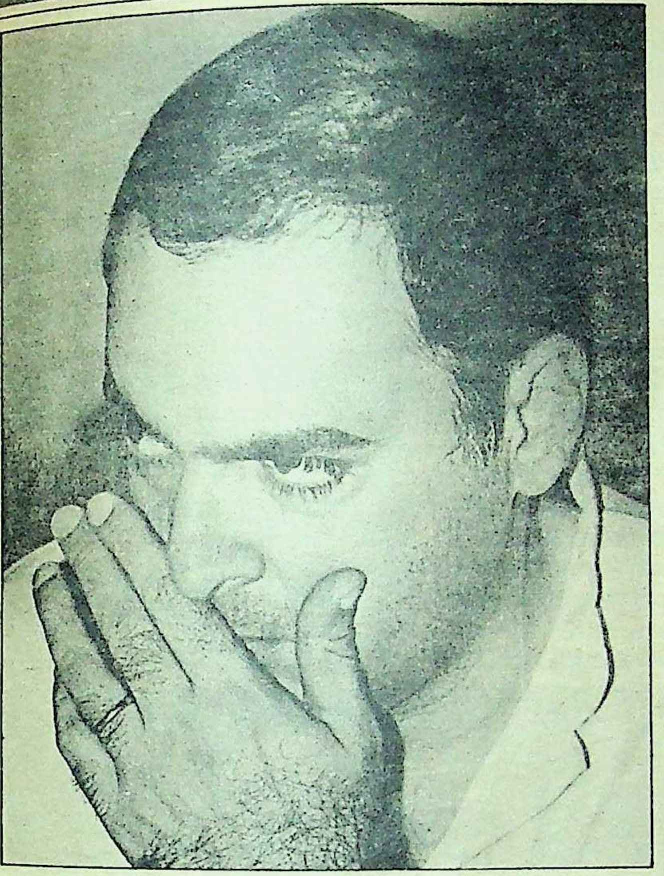

राजीव गांधी को खतम करने के लिए बचा ही क्या है? वे तो डोर से लटके कठपुतले हैं। कभी ललित सूरी खींच लेगा, कभी धवन खींच लेगा, कभी हिंदूजा खींच लेंगे, कभी अमिताभ बच्चन खींच लेंगे, तो कभी क्वात्रोची (स्नैम प्रोजेटी के प्रतिनिधि)।

मायाः *क्या प्रधानमंत्री-पद उन्होंने अपनी इच्छा के विपरीत स्वीकार किया था?*

नेहरूः *कतई नहीं। किसी वयस्क से जबर्दस्ती काम नहीं कराये जाते। मुझे तो इसकी अच्छी तरह जानकारी है, क्योंकि इस संबंध में उन्होंने मुझसे स्वयं बात की थी। श्रीमती गांधी की हत्या की खबर सुनते ही वे (राजीव गांधी) पश्चिम बंगाल से तुरंत दिल्ली लौटे। हवाई अड्डे से जब हम अस्पताल जा रहे थे, तो गाड़ी रुकवा कर उन्होंने बलराम जाखड़, प्रणब मुखर्जी को रास्ते में उतार कर मुझसे सीधे-सीधे कहा कि मैं तुरंत प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अंतरिम प्रधानमंत्री में मेरा विश्वास नहीं।*

मायाः *राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के शीघ्र बाद ही जब प्रणब मुखर्जी को काबीना से हटाया गया, तो अफवाह यह उड़ी थी कि ऐसा इस कारण किया गया है, क्योंकि उन्होंने नंबर दो होने के कारण अपनी प्रधानमंत्री-पद की दावेदारी पेश की थी।*

नेहरूः *शंकरानंद आदि ने यह खबर फैलायी थी कि प्रणब मुखर्जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वे कान के कच्चे हैं। इसलिए बात मान ली।*

मायाः *क्या धवन को संदेह की वजह से हटाया गया अथवा इसलिए कि इंदिरा वफादारों को दरकिनार किया जा रहा था?*

नेहरूः *आप प्रधानमंत्री से पूछिए। वफादारी शब्द बड़ा भ्रामक है। ठक्कर आयोग के सामने दिये गये पीएस एलेक्जेंडर के बयान को सार्वजनिक कर दें, तो सच्चाई से परदा हट जाये। सचाई एक-न-एक दिन बड़ी बेरहमी से सामने आ जाती है।*

मायाः *क्या विपक्ष दबाव डाल कर रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने में सफल होगा?*

नेहरूः *बात दबाव की नहीं है। यह (रिपोर्ट) तो खुदबखुद सामने आ जायेगी। कारण कोई कब तक १८० डिग्री मुड़ कर सुरक्षित रह सकता है। सीधी बात यह है कि जब दिमाग नहीं चलता, तो हाथ-पैर अधिक चलने लगते हैं। आजकल जितनी गाली-गलौज हो रही है, हवा में बात हो रही है, उससे यही जाहिर होता है। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं, नानी याद दिला देंगे, कभी कहते हैं सर काट देंगे। भारत के प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता। ऐसा तभी किया जाता है, जब अकल काम करना बंद कर देती है। यह सब भयाक्रांत मनःस्थिति का परिचायक है। यदि प्रधानमंत्री समझते हैं कि वे रॉ, सीबीआई, आईबी के सहारे सरकार चला सकते हैं, तो ठीक है। जनता के वोट भी उन्हीं से डलवा लेंगे। चुनाव तो सामने आ ही रहा है।*

मायाः *क्या समुचित विकल्प के अभाव में जनता परिवर्तन चाहेगी?*

नेहरूः *५ हजार वर्ष पुराने भारत में विकल्प की कमी नहीं। अगर पायलट प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ८० करोड़ हिंदुस्तानियों में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई अन्य प्रधानमंत्री होगा, तो कम-से-कम टेलीविजन पर दिखायी जानेवाली प्रेस कांफ्रेंस में विदेश सचिव को तो बर्खास्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि राजीव प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो देश ठप्प हो जायेगा। राजीव पहले हवाई जहाज चलाते थे। फिर चलायेंगे। देश में नहीं, तो विदेश में चलायेंगे।*

मायाः *जनता ने जनता दल से विकल्प पेश करने की जो आस लगायी थी, वह क्या आंतरिक कलह व संघर्ष से धूमिल नहीं हुई?*

नेहरूः *जब तीन-चार दलों का विलय होता है, तो कुछ-न-कुछ मतभेद होंगे ही। दो ही रास्ते होते हैं या तो तानाशाही रवैया अपना कर सबको मुंह सीलने को कह दिया जाये या विचार-विमर्श कर रास्ता निकालें। जनता दल के प्रति जनभावना का आकलन उसकी विशाल रैलियों और जनसभाओं को देखकर भलीभांति किया जा सकता है। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि अगले चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह मात खायेगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि उसे १२५ से एक सीट ज्यादा नहीं मिलेगी।*

मायाः *कर्नाटक में बोम्मई सरकार को गिराना*

कांग्रेस की हताशा की निशानी है या उनमें बढ़ते आत्मविश्वास और आक्रामक रवैये की?

नेहरू: *निशानी हताशा की है। जिस आदमी में हिम्मत होती है वह हाथ-पैर नहीं चलाता। गाली-गलौज करना, सरकारें गिराना बेचैनी की निशानी है। इतिहास से कोई सबक नहीं लेता। आखिर आपातकाल आया कैसे था? उस समय जो अक्ल की बात करता था, उसे सुना नहीं जाता था। फिर आपातकाल लादकर हजारों लोगों को जेल मे ठूस दिया गया। पांच महीने तक कारगर सरकार का गुणगान हुआ। किंतु उसके बाद जो चुनाव हुआ, उसमें श्रीमती गांधी हार गयी। १९७७ में जनता सरकार आयी। उसने भी परेशान किया और वह भी गयी। सबक यही मिलता है कि भारत की जनता दमनपूर्ण कार्रवाई बरदाश्त नहीं करेगी। यहां लोकतंत्र है। गरीब लोग चुप हो जाते हैं। पर मन बना लेने पर उन्हें कोई हिला नही सकता। जितना उन पर दबाव पड़ता है उनकी उतनी तीव्र प्रतिक्रिया होती है।*

माया: क्या आप आपातकाल पुनः दोहराये जाने की संभावना देख रहे हैं?

नेहरू: *बिलकुल। कर्नाटक प्रकरण इसका पहला संकेत है। आगे होगा यह कि ये (राजीव गांधी) सबका मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे। इस समय मुझ पर इसलिए हमला हो रहा है कि वे समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं। मुझे कोई नही डरा सकता। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी से अकेले निपट सकता हूं। मैं चुप बैठने वाला नही। आज ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मैंने पूछा है कि जिन ५० मुद्दों पर ठक्कर ने धवन को दोषी पाया था, उनका जवाब तो दीजिए। दूसरी बात, यदि एसआईटी जांच दल ने धवन को निर्दोष कहा है, तो उसका भी पूरा हवाला दीजिए। सचाई यह है कि एसआईटी ने ऐसी कोई 'क्लियरेंस' दी ही नहीं है। इसमें ये लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक-के बाद-एक झूठ बोलते जा रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे और कितनों का मुंह बंद करेंगे? अगर मेरा मुंह बंद कर लिया, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया, तो क्या पूरे देश का मुंह बंद कर देंगे? पूरे देश को फांसी पर चढ़ायेंगे? जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे कुरसी इनसे दूर भागेगी। तमिलनाडु की मिसाल सामने है। जिस मूपनार ने इनसे कंधा-से-कंधा मिलाकर काम किया, वहां चुनावी लड़ाई लड़ी, उसको थप्पड़ मार कर निकाल दिया। अन्य वफादारों के साथ भी यही किया है। उनके दिल पर क्या बीत रही होगी? इनके मन में किसी की भी इज्जत नहीं। न परिवार की इज्जत करते हैं, न दोस्तों की, न राजनीतिक सहयोगियों की। सारे संबंध अवसरवादिता के हैं। मानवीय संबंधों पर समझौता नही किया जा सकता। हमेशा प्रधानमंत्री बने रहने का कोई दैवी वरदान नहीं है। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब ही क्या होश में आयेंगे? मगर उस समय करेंगे क्या? भागेंगे और छिपेंगे कहा? कुरसी के नीचे तो छिप नही सकते।*

माया: क्या राजीव गांधी अपनी हार की आशंका से आम चुनाव टाल सकते हैं?

नेहरू: *टालेंगे कैसे? किस प्रावधान के तहत। एक दिन भी चुनाव नहीं टाल सकेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो देश की जनता इनको पकड़ कर...*

माया: विपक्षी राजनीति में आपकी क्या भूमिका है? यद्यपि आपका कोई आधिकारिक पद नहीं, किंतु आम धारणा है कि कांग्रेसनुमा अपनी पुरानी शैली में परदे के पीछे से आप मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

नेहरू: *मैं पर्दे के पीछे से कुछ नही करता। मैं जनता दल के संसदीय बोर्ड का सदस्य हू। उसमें होनेवाले विचार-विमर्श में निरंतर भाग लेता रहता हूं। पार्टी के रोजमर्रा के कार्य से मेरा कोई संबंध नहीं, पर उसके नीति-निर्धारण से मैं पूरी तरह जुड़ा हुआ हूं।*

सहानुभूति लहर जगाने के लिए उनकी कितनी बार टेलीविजन पर अंत्येष्टि करेंगे? भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं। वह यह देखे-परखेगी कि आपने (राजीव गांधी) क्या किया है?

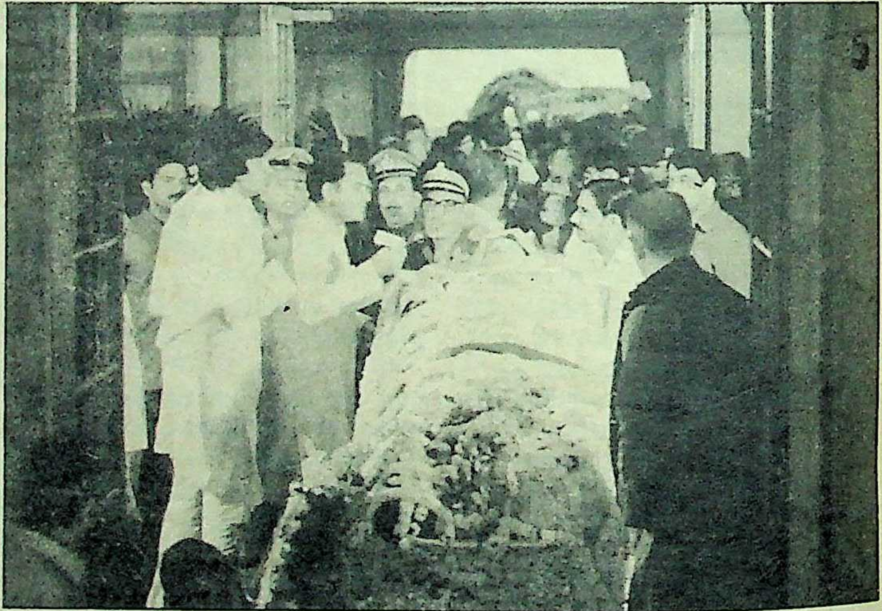

माया: जनता दल की मौजूदा अव्यवस्थित स्थिति में विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या स्थान है?

नेहरू: *वे हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व के प्रश्न को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं।*

माया: आप आम कार्यकर्ता स्तर से राजनीति में न आकर ऊपर से आये हैं। क्या जमीन से न जुड़े होने के अभाव में जनता को समझने-समझाने में आपको कठिनाई नहीं होती?

नेहरू: *जनता के सम्मुख जाने, समझने-समझाने में कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं जमीन से नहीं जुड़ा हूं, तो राजीव गांधी तो ३६ हजार फुट की ऊंचाई पर चक्कर काट रहे होंगे।*

माया: राजनीति में आप बहुत जल्दी ऊपर चढ़े, इसका क्या कारण है?

नेहरू: *मैंने जो कुछ हासिल किया, उसका श्रेय श्रीमती गांधी को है। उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ अवश्य देखा होगा।*

माया: जिस तेजी से ऊपर चढ़े, उसी तेजी और नाटकीय ढंग से आप नीचे क्यों आये?

नेहरू: *न नीचे आने का सवाल है, न नाटकीय परिवर्तन का। नीतियों के प्रश्न पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मेरे कई मुद्दों पर मतभेद थे, जिनके कारण कई बार मैंने इस्तीफा दिया जो*

बूटा सिंह के बेटों ने ७०० रुपए की वनस्पति कंपनी बनायी है और ९० लाख के शेयर ले लिये हैं। पैसा कहां से आया? क्या भगवान की देन है? यह बेईमानी नहीं, सरासर फ्राड (धोखाधड़ी) है।

मंजूर नहीं हुआ। कुरसी की परवाह न मुझे तब थी, न आज है।

माया: क्या निहित स्वार्थ वालों ने आपकी नीयत और कार्यशैली के खिलाफ राजीव गांधी के मन में संदेह पैदा किये थे?

नेहरू: अवश्य। क्वात्रोची, अमिताभ बच्चन जैसे बहुत थे, जिन्होंने भड़काने का काम किया।

माया: आपने राजीव गांधी को बहुत करीब से देखा है। उनके गुण-अवगुण क्या हैं?

नेहरू: मैं राजीव गांधी का कोई लेखा-जोखा नहीं रखता। पिछले तीन वर्षों से तो मैं मिला भी नहीं हूं। हां, इतना अवश्य जानता हूं कि दिन भर में दस बार उनका मत-परिवर्तन होता है। पिछले चार-पांच वर्षों में कोई भी मुद्दा उठाकर देखने से उनकी मत-परिवर्तन की यह विशेषता स्पष्ट होती है। कान के बेहद कच्चे हैं। दोष दूसरों के सर मंढ़ने में माहिर। श्रीलंका में गड़बड़ हो रही है, तो नंटवर सिंह को बलि का बकरा बना देंगे। तमिलनाडु में १३ बार जाने और करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हार गये, तो दोष मूपनार और चिदंबरम के मत्थे मंढ रहे हैं। पंजाब में आग लगा रहे हैं, तो पता नहीं कहां से उस शरीफ अरुण सिंह का नाम ले लिया है जो दूर पहाड़ में बैठा है। कह रहे हैं कि उसने १९८४ में गड़बड़ की थी। यदि मान भी लिया जाये कि उस समय कुछ हुआ, तो पिछले पांच वर्षों से ये क्या कर रहे हैं?

माया: पंजाब के मामले में सिर्फ अरुण सिंह ही नहीं, आपका नाम भी लिया जा रहा है।

नेहरू: मैंने तो बूटा सिंह से सीधा सवाल किया कि अकाल तख्त तुमने बनाया, सोना तुमने खरीदा, उसका तो हिसाब दो। किंतु जवाब ही नहीं देता। जवाब दे तो मैं यह और पूछूं कि जैसाकि वह यह कह रहा है कि उसने मुझसे बात की, तो उसने बात किस हैसियत से और किसके कहने पर की? वह काबीना मंत्री था। मैं तो मन्त्रिमंडल में नहीं था, तो क्या वह मुझे गोपनीय सरकारी सूचनाएं दे रहा था? मैं तो यह भी पूछ रहा हूं कि क्या ऐसा कर उसने अपनी गोपनीयता की शपथ भंग नहीं की? पर वह तो जवाब देता ही नहीं। जो आदमी झूठ बोलता है, वह जवाब नहीं दे सकता। वह तो अपने बेटों का व्यापार साम्राज्य बढ़ाने में अधिक व्यस्त है। बहुत ही भ्रष्ट आदमी है।

माया: राजीव गांधी इस समय धवन को क्या इसलिए वापस लाये हैं, क्योंकि वे चारों तरफ से घिर आये हैं?

नेहरू: राजीव गांधी क्या और क्यों करते हैं, इससे मुझे सरोकार नहीं। धवन की वापसी राजीव गांधी का निर्णय है। कांग्रेस पार्टी यदि धवन को राजीव का विकल्प समझती है, तो मुझे क्या? यदि अगले चुनाव में वे अपने चित्र की जगह धवन का चित्र टांगें, तो मुझे क्या लेना-देना?

माया: कहा जाता है कि धवन के सुपुर्द इस समय कांग्रेस को जोड़ने और विपक्ष को तोड़ने का काम है। क्या इस काम को पूरा करने की उनमें महारत है?

नेहरू: धवन कोई अहम मुद्दा नहीं। वह तो एक मामूली क्लर्क-किरानी है। सोचना आज यह है कि ठक्कर आयोग का सच अहम है या कुरसी बचाना? देश भर में आज यही सवाल उठाया जा रहा है कि अपनी कुरसी बचाने के लिए राजीव गांधी किन-किन सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं? क्या वे अपनी मां की हत्या के बारे में भी समझौता कर रहे हैं? वैसे इंदिराजी चार साल बाद याद आ गयी हैं। हाल के तमिलनाडु चुनाव में सिर्फ श्रीमती गांधी के पोस्टर लगाये गये थे। श्रीमती गांधी इस देश की १६ साल तक प्रधानमंत्री रहीं। उनकी विशेष इज्जत है। मुझे याद है कि १९८५ में जब पंजाब विधानसभा का चुनाव था, तब राजीव गांधी ने कहा था कि मैं उनका एक भी पोस्टर नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और मैं उनकी स्मृति को चुनाव में नहीं भुनाऊंगा। आज चार साल के बाद वही हरकत कर रहे हैं। सहानुभूति लहर जगाने के लिए उनकी कितनी बार टेलीविजन पर अंत्येष्टि करेंगे? भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं। वह यह देखे-परखेगी कि आप ने (राजीव गांधी) क्या किया है? इलाहाबाद चुनाव के दौरान शहर लाल बहादुर शास्त्री के पोस्टरों से पाट दिया गया। क्या सोचा था कि उसके सहारे सुनील शास्त्री को वोट मिलेंगे? आज ये बहुत हताश हैं। बदले की भावना से ये घटिया-से-घटिया काम करेंगे। कुरसी इनसे भाग रही है। यह उसे बचा नहीं पायेंगे। यह बात सिर्फ मैं ही नहीं, समूचे कांग्रेसी खेमे में चल रही है। मेरे हर स्तर पर निजी संपर्क हैं और मैं यह बात बखूबी जानता हूं।

माया: आप लोग जब कांग्रेस से बाहर आये थे, तो हवा बनी थी कि आपके साथ बहुतेरे कांग्रेसी आयेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्यों?

नेहरू: आये क्यों नहीं? जनमोर्चा का हर कार्यकर्ता पुराना कांग्रेसी है। कांग्रेसी का अर्थ मात्र सांसद, विधायक नहीं है। दल आम कार्यकर्ता से बनता है। इसकी हमारे पास कमी नहीं। यदि आज हम रायबरेली में कह दें, तो दस हजार लोग अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। आम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जिसके पास पद होता है, वह पद बचाने में ही जुटा रहता है। जिसके पास घोड़ा गाड़ी है, वह उसे ही बचाने की कोशिश करता है। और आजकल तो यह घोड़ा गाड़ी कुछ ज्यादा दी जा रही है। जब कुरसी जाती दिखायी देती है, तो पार्टी ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देती है। अमेठी में १०० जीपें पांच साल से लगातार चल रही हैं। एक ब्लाक प्रमुख है, तो उसके दो सहायक हैं और सबके पास एक-एक जीप हैं। वह अपनी जीप का परित्याग कैसे करे? उसे महीने में मात्र एक बार राजीव गांधी का नारा लगाना होता है और जीप चलाता है, वह तीसों दिन। पर आम कार्यकर्ता की बात भिन्न होती है। उसे कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी पार्टी संगठन, चाहे वह कांग्रेस हो या जनता दल, आम कार्यकर्ताओं से ही बनता-चलता है।

माया: कांग्रेसियों का दावा है कि आप रायबरेली की अपनी सीट नहीं बचा पायेंगे?

नेहरू: *यह उनकी राय है। पहले अपनी सीट तो बचा लें।*

माया: *१९८४ में आपने विपक्षी नेताओं के विरुद्ध चुन-चुनकर ऐसे उम्मीदवार खड़े किये थे कि उनकी मात पक्की हो...*

नेहरू: *हम तो इस बार भी यही करेंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि कौन कहां भाग रहा है। उप्र में जितने नेता (कांग्रेसी) हैं, सब इधर-उधर सीट देख रहे हैं। शीला दीक्षित उन्नाव जाना चाहती हैं। जेआर अंसारी अमरोहा जाना चाहते हैं। मोहसिनाजी लखनऊ जाना चाहती हैं। राजेंद्र कुमारी वाजपेयी इलाहाबाद जाना चाहती हैं।*

माया: *जहां तक भागने का सवाल है, अफवाह है कि स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे।*

नेहरू: *विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो सार्वजनिक रूप से घोषणा की है। किंतु वे हार के डर से वहां से नहीं जा रहे हैं। हमारी सोची-समझी योजना के तहत जा रहे हैं।*

माया: *क्या भ्रष्टाचार अभी भी आप लोगों का मूल मुद्दा रहेगा?*

नेहरू: *हां, क्यों नहीं? हम तो रोज इसकी बात उठाते हैं। मैंने आज ही बूटा सिंह को चिट्ठी लिखी है। राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी है। मैंने सीधे कहा है, तुम्हारी सरकार 'दाम दो काम लो' की सरकार है। कल आइये और ताजमहल खरीद कर ले जाइये। यह मजाक नहीं तो और क्या है कि बूटा सिंह के बेटों ने ७०० रुपए की वनस्पति कंपनी बनायी है और ९० लाख के शेयर ले लिये हैं? पैसा कहां से आया? क्या भगवान की देन है? यह बेईमानी नहीं, सरासर फ्राड (धोखाधड़ी) है। मैंने राजीव को यह भी लिखा है कि यदि बूटा सिंह और शिवचरण माथुर इस्तीफा नहीं देते, तो मैं यही समझूंगा कि आप भी इसमें शामिल हैं।*

माया: *क्या आप प्रधानमंत्री से इस पर कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं?*

नेहरू: *वे क्या कार्रवाई करेंगे? वे तो अपनी परछाईं से भी घबराते हैं। सब ब्लैकमेल करेंगे। बूटा सिंह गृहमंत्री हैं और आप (राजीव) जिस षड्यंत्र का ईजाद कर रहे हैं, उसकी आधी चीजें आप इसी (बूटा सिंह) के जरिए करायेंगे—चाहे वह जालसाजी हो या कुचक्र। ऐसे में उसके खिलाफ आप कार्रवाई कैसे करेंगे? बूटा सिंह के बारे में हर अखबार-मैगजीन में जांच-पड़ताल चल रही है और अगले १०-१५ दिन में हर जगह छप जायेगा, तो क्या राजीव गांधी को जानकारी नहीं कि किस प्रकार यह धोखाधड़ी हुई है? बूटा सिंह के बेटों की एक ट्रेवेल एजेंसी है। अब सुनने में आया है कि एक टैक्सी सर्विस भी है और एक खेलकूद पत्रिका भी है। पता नहीं कहां-कहां क्या-क्या कहा है?*

माया: *अगले चुनावों में मूल मुद्दा क्या होगा?*

नेहरू: *प्रमुख मुद्दा हर भारतीय के आत्म-सम्मान का होगा। स्वदेशी बनाम विदेशी का होगा। ८० करोड़ का देश है। पर हालात ये हैं कि आज स्वीडन आकर आपको लात मार जाता है। स्विट्जरलैंड आ जायेगा, तो वह लात मार जायेगा। इटली चाहेगा, तो वह लात मार जायेगा। जो आता है, वह लात मार जाता है। आपकी इज्जत कहां रही? ऐसा लगता है कि हम पुनः विदेशी सत्ता के मातहत हो गये हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, तो स्नैम प्रोजेटी आ गयी है। स्नैम प्रोजेटी नहीं होगी, तो बोफोर्स आ जायेगी। बोफोर्स नहीं होगी, तो एचडीडब्लू पनडुब्बी होगी।*

माया: *ठक्कर जांच रिपोर्ट के भंडाफोड़ में तो आपको फंसाने का प्रयास है ही। किंतु हाल की गतिविधियों से ऐसा लगने लगा है कि चेक पिस्तौल के मामले में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है।*

मैंने पूछा है कि जिन ५० मुद्दों पर ठक्कर ने धवन को दोषी पाया था, उनका जवाब तो दीजिए। दूसरी बात, यदि एसआईटी जांच दल ने धवन को निर्दोष कहा है, तो उसका भी पूरा हवाला दीजिए। सचाई यह है कि एसआईटी ने ऐसी कोई 'क्लियरेंस' दी ही नहीं है।

नेहरू: *वे जो चाहे कर सकते हैं। राजीव गांधी की सरकार तो ऐसी है कि उसे वहां भ्रष्टाचार दिखायी देता है, जहां सौदा ही नहीं हुआ। असलियत खुदबखुद सामने आ जायेगी। अक्ल की बात है कि जब सौदा ही नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार कैसा? मैं तो चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, तब मैं उनको बेनकाब कर दूंगा। हिम्मत हो, तो मुझे गिरफ्तार करें।*

माया: *ऐसा लगता है कि आप दोनों (राजीव-अरुण) ही इस समय एक दूसरे को मात्र घायल करने के लिए प्रयासरत हैं, खतम करने के लिए नहीं। क्या आपने ब्रह्मास्त्र अंतिम युद्ध (चुनाव) के लिए सुरक्षित कर रखा है?*

नेहरू: *ये सब महज अटकलबाजियां हैं। पहले दिन से ही वे बहुत क्षुद्र मनोवृत्ति के शिकार रहे हैं। मेरे खिलाफ क्या-क्या नहीं किया? जब मेरी बेटी की सगाई हुई, तो सीताराम केसरी से चिट्ठी लिखवायी। आज पूरे नेहरू परिवार से अलग क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी की शादी में अपनी शक्ल नहीं दिखायी। हमारी राजनीतिक लड़ाई है, तो उसे राजनीतिक अखाड़े में लड़ना चाहिए। बीवी-बच्चों को उसमें क्यों घसीटो? यह तो नीचपना है और यही दुखद है। राजनीति में तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा। प्रधानमंत्री बने रहना किसी की जमींदारी नहीं।*

माया: *क्या अंतिम प्रहार ऐन चुनाव पूर्व करेंगे?*

नेहरू: *राजीव गांधी को खतम करने के लिए बचा ही क्या है? वे तो डोर से लटके कठपुतले हैं। कभी ललित सूरी खींच लेगा, कभी धवन खींच लेगा, कभी हिंदूजा खींच लेंगे, कभी अमिताभ बच्चन खींच लेंगे, तो कभी क्वात्रोची (स्नैम प्रोजेटी के प्रतिनिधि)। आज वे कौन सा निर्णय अपने आप लेते हैं? अपनी कांग्रेस पार्टी में भी निर्णय नहीं ले सकते। मप्र में माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, बन गये मोतीलाल वोरा। बिहार में तारिक अनवर को बनाना चाहते थे, बन गये सत्येंद्र बाबू। राजस्थान में लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। दो महीने बाद देख लीजिएगा क्या होगा?*

माया: *आपने जिसे बनाया उसे तोड़ते हुए क्या आपको दुख नहीं होता?*

नेहरू: *जो अपने आपको तोड़ रहा है, उसे तोड़ने की क्या जरूरत? हालत यह है कि कमरतोड़ महंगाई है और आप टेलीविजन पर क्या बात कर रहे हैं? 'रन फार योर कंट्री,' 'रन फार पेप्सी कोला,' 'रन फार थम्स-अप,' 'रन फार वाटर बरीज कंपाउंड'। भारत के प्रधानमंत्री ट्रैक सूट पहन कर भाग रहे हैं। यह कैसा मजाक है!*

—रंजना कक्कड़

कैसे चल रही है, तिवारी-सरकार ?

अपना-अपना दांव : नारायण दत्त दिवारी, बलराम सिंह यादव, राजीव और सोनिया गांधी छाया : मनमोहन शर्मा

अब वह समय निकट है जब उत्तर प्रदेश केंद्र में नयी सरकार चुनने में निर्णायक भूमिका निभायेगा। आगामी चुनावी युद्ध में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-इ फौज का नेतृत्व का भार फिलहाल मंजे हुए और अनुभवी नेता नारायण दत्त तिवारी पर है। सवाल उठता है क्या तिवारी अपनी सरकार के जरिये ऐसा माहौल बना पा रहे हैं, जिससे जनता कांग्रेस-इ को वोट देने का मन बना सके ? अधिसंख्य कांग्रेसी विधायक स्वयं तिवारी पर तो नहीं, लेकिन उनके मंत्रियों पर संगीन आरोप लगाने में लगे हैं। चुनावों के और समीप आने पर आरोप लगाने की गति और तेज होने के आसार हैं। ऐसी स्थिति में क्या तिवारी पार्टी के आंतरिक झगड़ों से निजात पा कर पार्टी को जीत की ओर अग्रसर कर सकेंगे ? उनकी सरकार चुनाव की पूर्व संध्या पर किस स्थिति में है ?

उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी विधायकों को भी असंतोष का छुतहा रोग लगना शुरू हो गया है। हां, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह इसने यहां महामारी का रूप नहीं लिया है। उत्तर प्रदेशी असंतोष में एक भिन्नता यह भी है कि यहां नेतृत्व-परिवर्तन की गुहार नहीं लगायी जा रही, बल्कि मंत्रिमंडल और दल के ढांचे में आमूल बदलाव की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। १८ मार्च को राज्य विधानमंडल के २६७ में से १४४ विधायकों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देकर यही बात कही है। ज्ञापन में वही पुरातन आरोप दोहराये गये हैं कि मंत्रिपरिषद के अनेक मंत्री भ्रष्ट हैं, विधायकों का वे कार्य नहीं करते, अफसर उनके हुकुम नहीं मानते आदि। आखिर में आरोपों की तान इस बात पर टूटती है कि हालत यही बनी रही, तो प्रदेश का विकास संभव नहीं है और इसका नतीजा यह होगा कि आगामी चुनाव में पार्टी की बधिया बैठ जायेगी। केंद्रीय राज्यमंत्री शीला दीक्षित से मिलकर भी असंतुष्टों ने अपने इन्हीं आरोपों को दोहराया है।

ऐसा नहीं है कि असंतुष्टों के आरोप बिलकुल निराधार हैं, पर यह भी नहीं है कि सारे असंतुष्ट मात्र पार्टी की भलाई के लिए ही व्याकुल हैं। अनेक की बेचैनी का सबब यह भी है कि उन्हें आगामी चुनाव में पार्टी से सत्ता छिन जाने की आशंका है। अत: जब तक पार्टी सत्ता में है, तब तक सत्ता को जितना दुह लिया जाये, वे दुहने की फिराक में हैं। दुहने का एक मात्र जरिया मंत्री-पद है या ऐसे ही लाभ का कोई और पद हथिया लेना है। शायद यही कारण है कि असंतुष्ट मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते।

तिवारी के बारे में बोलने की वैसे भी हिम्मत असंतुष्टों में नहीं। तिवारी तपे हुए कांग्रेसी हैं और केंद्र तथा राज्य में उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता को असंदिग्ध रूप से सिद्ध किया है। लेकिन उनकी कमजोर नस वे मंत्री बन गये हैं, जिन पर असंतुष्टों को भ्रष्टाचार व अयोग्यता का आरोप लगाते समय ज्यादा सोच-विचार नहीं करना पड़ता।

मंत्रियों पर प्रहार : मंत्रियों की जिस टीम के बल पर नारायण दत्त तिवारी प्रदेश में विकास का माहौल निर्मित कर कांग्रेस-इ के पक्ष में चुनावी लहर पैदा करना चाहते हैं, उनके बारे में खुद कांग्रेसी विधायकों की राय अच्छी नहीं है।

प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस-इ के २४६ विधायक हैं, इनमें से १७० विधायकों का कहना है कि तिवारी मंत्रिमंडल के ४६ मंत्रियों में से ३६ मंत्री भ्रष्ट और अक्षम हैं। इन्हें निकालने के लिए इन्होंने बाकायदा हस्ताक्षर-अभियान चला रखा है।

तिवारी तपे हुए कांग्रेसी हैं और केंद्र तथा राज्य में उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता को असंदिग्ध रूप से सिद्ध किया है। लेकिन उनकी कमजोर नस वे मंत्री बन गये हैं, जिन पर असंतुष्टों को भ्रष्टाचार व अयोग्यता का आरोप लगाते समय ज्यादा सोच-विचार नहीं करना पड़ता।

मंत्रियों की अक्षमता साबित करने के लिए असंतुष्टों के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि विधानसभा में श्रम विभाग से संबंधित सवालों के जवाब श्रममंत्री सईदुल हसन नहीं, बल्कि वन राज्यमंत्री जगदंबिका पाल देते हैं। इसी तरह सुशीला रोहतगी गृह-विभाग देखती हैं, लेकिन विधानसभा में गृह-विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने का दायित्व निभाते हैं, शिक्षा राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान। चौहान वीर बहादुर सिंह की सरकार में गृहराज्य मंत्री रहे हैं। बजट सत्र में उन्होंने ही गृह-विभाग से संबंधित सवालों के जवाब दिये। और-तो-और, वास्तविक गृहमंत्री की संज्ञा गृहसंचिव संतकुमार त्रिपाठी को दी जाती है। केंद्रीय राज्यमंत्री शीला दीक्षित के चुनाव क्षेत्र के होने की बख्शीश के रूप में मंत्री बनाये गये बिहारी लाल दोहरे का तो आलम यह है कि एक बार जब उन्हें विधानसभा में एक सवाल का लिखित उत्तर पढ़ना पड़ा, तो उनके हाथ-पैर कांपने लगे, गला सूख गया, वे पसीने-पसीने हो गये और लिखित उत्तर तक नहीं पढ़ सके।

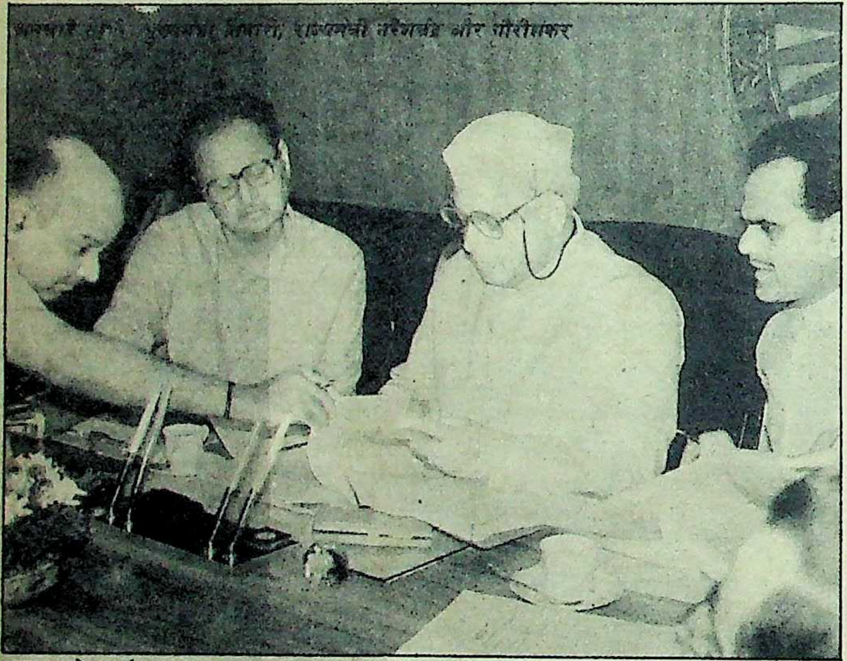

[illegible] मुख्यमंत्री तिवारी, राज्यमंत्री नरेशचंद्र और गौरीशंकर

छाया: मनमोहन शर्मा

मंत्रियों की जिस टीम के बल पर नारायण-दत्त तिवारी प्रदेश में विकास का माहौल निर्मित कर कांग्रेस-इ के पक्ष में चुनावी लहर पैदा करना चाहते हैं, उनके बारे में खुद कांग्रेसी विधायकों की राय अच्छी नहीं है।

कोई मंत्री मुख्यमंत्री को सीधा आदेश (डीओ), नहीं दे सकता, लेकिन जाली डिग्री के लिए चर्चित श्रीमती बेनीबाई ने अपने लघु एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सुधार करने से संबंधित एक डीओ पत्र मुख्यमंत्री को ही भेज दिया जो घूम-फिरकर उन्हीं के पास आ गया, लेकिन सरकारी अफसरों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ायी।

सर्वाधिक 'कमाऊ मंत्री' के रूप में पुकारे जानेवाले सार्वजनिक निर्माण मंत्री अम्मार रिजवी के मंत्रालय के बारे में तो स्वयं प्रधानमंत्री ने अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन के निर्माण के संबंध में १४ अप्रैल को लखनऊ में बोलते हुए चुटकी ली थी, "हमें देखना है कि यह भवन मजबूत बने। वैसे नहीं जैसे मेरे क्षेत्र (अमेठी) में बन रहे हैं जो बनते ही ढहने लगते हैं।" एक मंत्री हैं, अजीत सेठी (राज्यमंत्री शिक्षा, नगर विकास)— उन्हें मंत्री-पद की शपथ लेने लखनऊ आने के लिए फोन किया गया, लेकिन कहते हैं, वे शपथ लेने पहुंच गये, दिल्ली। गुलाब सिंह, स्वरूपरानी बख्शी और बलदेव सिंह आर्य वृद्ध हैं और अकसर बीमारी की वजह से अशक्त रहते हैं।

झगड़ों में उलझे मंत्री : तिवारी-मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों में तो आपस में खींचातानी है ही! अनेक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से भी उनकी पटरी नहीं बैठती है। इस आपसी उठापटक का असर प्रशासन पर पड़ना लाजिमी है। अम्मार रिजवी वन राज्यमंत्री जगदंबिका पाल को फूटी आंख नहीं सुहाते। दूसरी ओर, पाल का सांसद काजी जलील अब्बासी और साथी मंत्री अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना' से छत्तीस का रिश्ता है। ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्यमंत्री श्याम सूरत उपाध्याय का केंद्रीय मंत्री राजेंद्र कुमारी वाजपेयी से टकराव है। दोनों इलाहाबाद के हैं। वाराणसी की राजनीति में सिंचाई मंत्री लोकपति त्रिपाठी और राज्यमंत्री श्रीनाथ सिंह एक दूसरे का नाम लेने से पहले 'आधा दर्जन' उपाधियां जोड़ते हैं। कालाकांकर के दिनेश सिंह और प्रतापगढ़ के अजीत प्रताप सिंह (वनमंत्री) में तगड़ी लागडाट है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री कोकब हमीद केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते। सईदुल हसन की कोकब हमीद और समरपाल सिंह से नहीं पटती, तो झांसी की बेनीबाई ओमप्रकाश रिछारिया को नीचा दिखाने के किसी मौके को खोना नहीं चाहतीं। कानपुर के शिवनाथ सिंह कुशवाहा (राज्यमंत्री लोक निर्माण) और ऊर्जा मंत्री नरेंद्र सिंह पीछे नहीं, तो सूचना राज्यमंत्री नरेशचंद्र को राज्यमंत्री नियोजन गौरीशंकर का सार्वजनिक रूप से कालर पकड़ने में संकोच नहीं होता।

तुष्टीकरण की नीति : मंत्रियों का हाल ही बेहाल नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर आर्थिक संकटों का भी सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश के सरकारी उपक्रम प्रतिदिन पौने दो करोड़ से अधिक का घाटा दे रहे हैं। तिवारी के ही अनुसार सरकार इस समय ८०० करोड़ रुपए के घाटे में है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि से १२०० करोड़ रुपए भी निकाल लेने का फैसला किया गया है। यदि उससे प्राप्त होनेवाले ब्याज को भी घाटे में जोड़ लिया जाये, तो १९८९-९० के वित्तीय वर्ष में यह घाटा बढ़कर एक हजार करोड़ रुपए हो जायेगा। इस घाटे के बावजूद तिवारी अपने विधायकों को तुष्ट करने के लिए मजबूर हैं। राज्य के लिए नये संसाधन जुटाने के बजाय अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए तमाम विधायकों और सेवानिवृत्त राजनेताओं को खुश रखने के उद्देश्य से तिवारी ने पदों का

उपहार बांटना शुरू कर दिया है। तिवारी-मंत्रिपरिषद में जितनी संख्या में मंत्री और राज्यमंत्री हैं, उससे कहीं अधिक मंत्री-स्तर के लोग मंत्रिपरिषद से बाहर हैं। दर्जनों लोगों को विभिन्न निगमों का अध्यक्ष बना कर उनके लिए गाड़ी-घोड़े की व्यवस्था कर दी गयी है। यही नहीं, राज्य के भूतपूर्व मुख्यसचिव त्रिभुवन प्रसाद तिवारी को भी आर्थिक वित्तीय सलाहकार बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। प्रदेश एग्रो पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रहा है। लेकिन घाटे को दूर करने के बजाय विधान परिषद के पूर्व सभापति वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल को इसका अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट स्तर का दर्जा दे दिया गया है। यानी हार्टिको पर प्रतिमाह लगभग ४० हजार रुपए का खर्च और बढ़ गया है। डा० परिपूर्णानंद वर्मा को भी बेकारी पेंशन दे दी गयी है। इस तरह प्रशासकीय खर्चों में बेपनाह वृद्धि हो गयी है।

नये जिले, नया खर्च : पिछले वर्ष विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में नये जिलों के गठन का अभी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इससे प्रशासकीय व्यय बढ़ जाता है। इसके लिए केंद्रीय योजना आयोग हमें अनुमति नहीं देता। किन्तु तिवारी ने और कुछ किया या नहीं, अपने दस महीने के कार्यकाल में बिना मुख्यालय और क्षेत्रों का निर्धारण किये, छह नये जिलों के शिलान्यास-पत्थर लगा ही दिये। नतीजतन, पूरे प्रदेश में एक तूफान खड़ा हो गया। पडरौना, कुशीनगर, बलरामपुर, भदोही, महोबा, चित्रकूट आदि को जिला बनाने के उग्र आंदोलन छिड़ गये। पहाड़ में बागेश्वर को जिला बनाने की मांग तेज हो गयी, तो सोनभद्र, हरिद्वार और मऊ के मुख्यालय कहां हों, इस बात को लेकर लाठी चल रही है। देवरिया जिले में तमकुही तहसील के मुख्यालय को लेकर दो कांग्रेसी विधायक श्रीमती शशि शर्मा और रामसकल तिवारी में सिर-फुटौवल के डर से मुख्यमंत्री तहसील मुख्यालय का शिलान्यास करने नहीं गये। इसी तरह टाउन एरिया, नगरपालिका, महापालिका और तहसील बनाने के प्रश्न पर मुरादाबाद, पयागपुर, मेहदावल आदि में तीव्र जन-आंदोलन शुरू हो गये हैं। ऐसे समय जब प्रदेश भारी आर्थिक संकट में है, तब दो नये मण्डल, छह जिले और २६ तहसीलों के गठन की प्रक्रिया आरम्भ करके नारायणदत्त तिवारी ने स्वयं नयी झंझट मोल ले ली है।

कानून-व्यवस्था : प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है। एक मास में अकेले मेरठ मण्डल में एक दर्जन से अधिक सामूहिक हत्याएं हुईं, जिनमें ५० से अधिक व्यक्ति मारे गये। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का कोई हल नहीं निकल पा रहा। मुख्यमंत्री उच्चन्यायालय को अपनी ढाल बनाये बैठे हैं। भावना भड़कानेवाले इस विवाद में अदालत उलझना नहीं चाहती। राजनीतिक नेतृत्व भी इसे हाथ लगाने से कतरा रहा है। देवरिया जिले में जंगलपार्टी ने मरिचहवा गांव के १३ कोइरियों को मौत के घाट उतार दिया, तो लखीमपुर खीरी जिले में आतंकवादियों ने दो पुलिसकर्मियों समेत चार व्यक्तियों को गोली मार दी। इन दोनों बड़ी सामूहिक हत्याओं के सिलसिले में अब तक किसी को नहीं पकड़ा जा सका। अकेले लखनऊ शहर में आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है। हाल में ही नगर में एक भूतपूर्व विधायक रमाकांत मिश्र की दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी।

नारायण दत्त तिवारी के सामने समस्या यही नहीं है कि सरकार की शासन पर पकड़ ढीली तथा मंत्रियों और विधायकों की छवि धूमिल है, बल्कि रह-रहकर चलनेवाली ये अफवाहें भी उनका भारी सिरदर्द हैं कि 'तिवारी को भी जल्दी ही हटा दिया जायेगा।'

योग्यता पर प्रश्नचिह्न : राज्यमंत्री हितेश कुमारी और उनके पतिदेव

छाया : मनमोहन शर्मा

नेता बनाम अफसर : सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव है, मंत्रिमंडल की छवि धूमिल है और सबको साथ लेकर चलने की सहज प्रवृत्ति के कारण कभी-कभी 'मूंदहु आख कतहुं कछु नाहीं' की भंगिमा अपनाने के लिए तिवारी मजबूर हैं। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि जिस नौकरशाही के बलबूते पर तिवारी विकास कार्यों को अंजाम देना चाहते हैं, वह नौकरशाही मंत्रियों और विधायकों पर हावी होती जा रही है। हरिजन वित्त विकास निगम के प्रबंध निदेशक शंकरदत्त ओझा ने विधानसभा के गलियारे में विधायक हरदेव को पकड़कर इसीलिए पीट दिया, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री से उनके (ओझा के) खिलाफ शिकायत की थी। मामला विधानसभा में उठा और ओझा को क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक वरिष्ठ विधायक हरीशचंद्र श्रीवास्तव के साथ किया गया कथित दुर्व्यवहार भी काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। राज्यमंत्री चेतराम गंगवार के बरेली के तहसीलदार से ही नहीं, बल्कि बरेली के जिलाधिकारी आरके शर्मा से छिड़े विवाद ने तो इतना तूल पकड़ा कि

तिवारी-मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रियों में तो आपस में खींचातानी है ही! अनेक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से भी उनकी पटरी नहीं बैठती है। इस आपसी उठापटक का असर प्रशासन पर पड़ना लाजिमी है।

गंगवार मुख्यमंत्री तिवारी से ही भिड़ गये। कुछ माह पूर्व जब तिवारी ने गंगवार से पूछा कि बरेली नगर महापालिका के मेयर पद के लिए किसे टिकट देना ठीक होगा, तो गंगवार का जवाब था, "आप बरेली के जिलाधिकारी को मेयर का भी टिकट दे दें।" इस वार्तालाप के बाद तिवारी-गंगवार के बीच कोई बात नहीं हुई। गंगवार बरेली जिले की नवाबगंज तहसील के अपने गांव पचपेड़ा चले गये और महीनों से अपने गांव में ही हैं। बजट अधिवेशन में वे सिर्फ हाजिरी लगाने लखनऊ आये थे। इसी प्रकार बाराबंकी के कांग्रेस-इ के विधायक सुरेंद्रनाथ अवस्थी उर्फ पुत्तू अवस्थी ने तो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ब्रजलाल का तबादला करवाने के लिए तिवारी को धमकी तक दे डाली थी कि 'या तो ब्रजलाल बाराबंकी छोड़ेंगे, नहीं तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा।' मुख्यमंत्री को इस धमकी के आगे झुककर ब्रजलाल को अपने ही सचिवालय में सचिव बनाकर बुलाना पड़ा। ब्रजलाल की योग्यता-क्षमता को ध्यान में रखकर तीन वर्ष पूर्व उन्हें सिख उग्रपंथियों पर अंकुश लगाने के लिए पीलीभीत भेजा गया था, लेकिन कहा जाता है कि विधायक-विरोध के फलस्वरूप आज वे मुख्यमंत्री सचिवालय में फाइलें ढो रहे हैं। लेकिन चंद्रपाल और धर्मदेव मिश्र जैसे कुछ अफसर ऐसे भी हैं, जिनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। चंद्रपाल और धर्मदेव मिश्र के घरों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग ने छापे डाले और दोनों विभागों ने इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को लिखा, लेकिन इन दोनों अफसरों का बाल-बांका तक नहीं हुआ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के बहुचर्चित मुख्य अभियंता गुप्त के खिलाफ सतर्कता जांच चल रही है। सतर्कता विभाग ने सरकार को लिखा कि गुप्त को लखनऊ विकास प्राधिकरण से हटा दिया जाये। सरकार ने गुप्त को लखनऊ विकास प्राधिकरण से हटाकर कई गुना बड़े गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सिर पर बिठा दिया। मंत्रियों पर अफसर किस कदर हावी हैं, इसका एक प्रसंग विधानसभा के गलियारों में अच्छा-खासा चर्चित है। श्रममंत्री सईदुल हसन अपने पद और प्रतिष्ठा का सारा लिहाज ताक पर रखकर परगना मजिस्ट्रेट का तबादला रुकवाने के

छाया: राजेंद्र कुमार

आरोप विचारणीय: केंद्रीय राज्यमंत्री शीला दीक्षित

तीन की लागडाट : तिवारी की काट

नारायणदत्त तिवारी की परेशानी यही नहीं है कि मंत्रिपरिषद में उनके कुछ सहयोगियों पर भ्रष्टाचार और अयोग्यता के आरोप हैं, बल्कि यह भी है कि उनकी टांग खींचनेवाले भी कम नहीं हैं। जो नारायणदत्त तिवारी की कुर्सी पर नजर टिकाये उसे उलटने में जुटे हैं, उनमें सबसे पहला नाम पिछले मुख्यमंत्री और वर्तमान संचार मंत्री वीरबहादुर सिंह का है। हालांकि तिवारी कहते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और वीरबहादुर सिंह भी यह कहने से नहीं सकुचाते कि 'लखनऊ आने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं,' पर जहां भी मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे के नश्तर लगाते हैं। महराजगंज के विधायक रामलच्छन प्रसाद ने जब वीरबहादुर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और अनशन पर बैठे, तब तिवारी सरकार के दो मंत्रियों ने जाकर उनका अनशन तुड़वाया और उनकी मांगों पर गौर किये जाने का आश्वासन दिया। बलराम सिंह यादव ने तिवारी से कहा कि रामलच्छन प्रसाद को कांग्रेस विधायक दल की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाये, पर तिवारी ने इस सिफारिश पर कान ही नहीं दिया। वीरबहादुर सिंह ने जिन इंजीनियरों को लखनऊ से बाहर फेंका था, वे तिवारी के आते ही फिर लखनऊ लौट आये।

वीरबहादुर सिंह ने अल्पसंख्यकों के सम्मेलन में तिवारी सरकार पर आरोप लगाया, "उसने उन सब कार्यक्रमों पर 'पूर्ण विराम' लगा दिया जिन्हें मैंने शुरू किया था।" जवाब में गोरखपुर के निर्दलीय विधायक हरिशंकर तिवारी ने वीरबहादुर पर आरोप लगाया, "उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से करोड़ों रुपये की संपत्ति बटोरी है। वे मुझे मरवा डालना चाहते हैं। केंन्द्रीय संचार मंत्री की इन सब बेईमानियों की जांच करायी जाये।"

लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिलान्यास के मौके पर आयोजित सभा में वीरबहादुर सिंह ने प्रधानमंत्री के सामने कहा, "दरअसल इस विश्वविद्यालय के लिए २५ लाख रुपये देने की घोषणा मैंने वर्ष भर पहले आगरा में ही कर दी थी।" जाहिर है, अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय वीरबहादुर सिंह बटोरना चाहते थे। नारायणदत्त तिवारी ने बारी आते ही जवाब दिया, "आगरा की घोषणा तो आगरा के लिए थी। वहीं रह गयी। अंबेडकर विश्वविद्यालय की इस योजना के लिए तो मैंने ढाई करोड़ रुपये की व्यवस्था अब की है। सात करोड़ और दिये जायेंगे। कुल योजना १.११ अरब रुपये की है।"

प्रत्येक योजना पर अपना ठप्पा लगा कर और तिवारी सरकार को सब तरह से अयोग्य और निष्क्रिय बताकर वीरबहादुर सिंह अपनी लखनऊ वापसी की चर्चा के चिराग में तेल डालते रहना चाहते हैं, तो तिवारी समर्थक यह यकीन दिलाने में जरा भी कोताही नहीं बरतते, "जाकर लौटनेवालों में, गौतम बुद्ध की तरह बार-बार लौटनेवाले अकेले नारायण दत्त तिवारी हैं। उनके अतिरिक्त ऐसा कौन है, जो जाकर फिर लौटा हो?"

प्रत्येक योजना पर अपना ठप्पा लगा कर और तिवारी सरकार को सब तरह से अयोग्य और निष्क्रिय बताकर वीरबहादुर सिंह अपनी लखनऊ वापसी की चर्चा के चिराग में तेल डालते रहना चाहते हैं, तो तिवारी समर्थक यह यकीन दिलाने में जरा भी कोताही नहीं बरतते, "जाकर लौटनेवालों में, गौतम बुद्ध की तरह बार-बार लौटनेवाले अकेले नारायणदत्त तिवारी हैं। उनके अतिरिक्त ऐसा कौन है, जो जाकर फिर लौटा हो?"

कृष्णचंद्र पंत चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठें, जिसे १९३७, फिर चालीस के दशक के अंत और पचास के आरंभ में उनके पिता गोविंद बल्लभ पंत ने सुशोभित किया था। पर नारायणदत्त तिवारी ने पंत का निर्वाचन क्षेत्र नैनीताल ही नहीं छीना, उनको उत्तर प्रदेश से भी निकाल बाहर किया है। अपनी पत्नी इला पंत के माध्यम से कृष्णचंद्र पंत ने रेसकोर्स रोड तक अपनी सुरंग फोड़ ली है और पीएम हाउस में मौका देखकर वे यह स्वर गुंजाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनावी जहाज नारायणदत्त तिवारी किनारे नहीं लगा सकते।

बलराम सिंह यादव: नारायणदत्त तिवारी को दबा कर रखने के लिए वीरबहादुर सिंह ने बलराम सिंह यादव को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा कर लखनऊ में बैठाया। बलराम सिंह यादव ने शुरुआत अच्छी की। प्रदेश कांग्रेस को

लिए मुख्य सचिव के पास तक पहुंच गये, तो मुख्य सचिव को कहना पड़ा, "सर, इसकी आपको क्या जरूरत पड़ी? मैं स्वयं आपके पास शिष्टाचारवश हाजिर हो जाता।"

चुनौतियां: वीरबहादुर सिंह ने उत्तर प्रदेश की सत्ता नारायण दत्त तिवारी को सौंपते हुए कहा था कि वे प्रदेश को समस्यारहित करके जा रहे हैं, लेकिन तिवारी जानते थे कि दरअसल समस्याओं का अंबार लग जाने के कारण ही वीरबहादुर का गमन और उनका प्रदेश में आगमन हुआ है। तब उनके लिए यह सवाल कोई मायने नहीं रखता था कि केंद्रीय वित्तमंत्री पद से मुख्यमंत्री बनना उनका अवमूल्यन है या नहीं, क्योंकि तब उनके लिए यह बात अधिक महत्वपूर्ण हो गयी थी कि उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव-निर्णायक प्रदेश की बागडोर सौंपकर राजीव गांधी ने उन पर असीम विश्वास व्यक्त किया है। कांग्रेस-इ के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि कांग्रेस-इ की गिरती साख और वीपी सिंह की लोकप्रियता की उठान को कैसे थामा जाये और यह माहौल कैसे बनाया जाये कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस-इ सरकार ही प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकती है।

छाया: मनमोहन शर्मा

दुविधा का दौर: बलराम सिंह यादव

लेकिन उत्तर प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी के सामने समस्या यही नहीं है कि सरकार की शासन पर पकड़ ढीली तथा मंत्रियों और विधायकों की छवि धूमिल है, बल्कि रह-रहकर चलनेवाली ये अफवाहें भी उनका भारी सिरदर्द हैं कि 'तिवारी को भी जल्दी ही हटा दिया जायेगा।' उनके दस मास के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर फर्क सिर्फ यह आया है कि जहां वीपी लहर कुछ थमी है, वहीं प्रदेश में वीरबहादुर सिंह की दखलंदाजी भी कम हुई है और रामनरेश यादव के कांग्रेस-इ में आने से प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष बलराम सिंह यादव का तिवारी-विरोधी रुख नरम पड़ा है, लेकिन आसन्न चुनाव की जो चुनौती तिवारी के सामने है और समय जितना कम है, उसे देखते हुए तिवारी को अभी बहुत कुछ करना है। उनकी नेतृत्व की योग्यता और प्रशासनिक क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन देखना है कि वे प्रदेश की जटिल समस्याओं से कैसे उबरते हैं।

—अजय कुमार

नारायणदत्त तिवारी की छाया से दूर रखा।

नारायणदत्त तिवारी ने इस दृष्टि से तो अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया कि बलराम सिंह यादव को वीरबहादुर सिंह से मिलानेवाले तार काट दिये। बलराम सिंह यादव को समझाया गया, "वीरबहादुर को फिर मुख्यमंत्री बना कर लाने की बजाय आप स्वयं क्यों न इस कुर्सी के दावेदार बनें?"

नारायणदत्त तिवारी की विरोधी शक्ति दो खेमों में बंट कर बिखर गयी। तिवारी ने दूसरा पत्ता खेलते हुए जिला परिषदों के अध्यक्षों के चयन में बलराम सिंह को कोई प्रमुख भूमिका नहीं सौंपी। सोनिया गांधी के जन्मदिन का तमाशा हुआ, जिससे अध्यक्ष बलराम सिंह की प्रतिष्ठा औंधे मुंह गिरी। बलराम सिंह यादव ने तिवारी मंत्रिपरिषद के कुछ 'उदंत बछड़ों' और गुलाम नबी आजाद को पकड़कर एक नयी चौकड़ी तैयार की। इस चौकड़ी ने तिवारी के हटाये जाने और नये नेता की खोज होने की हवा को नयी गति दी। पर तिवारी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं। यादव के जहर के दांत तोड़ने के लिए वे दूसरे यादव रामनरेश को पकड़ लाये। बलराम सिंह के विरोधी रामनरेश सिंह यादव, नारायणदत्त तिवारी के प्रशंसक हैं। बलराम सिंह यादव ने लखनऊ के समाचारपत्रों में ऐसी अटकलें छपवानी शुरू कीं जिनका आशय था, 'तिवारी की भीत गिरी, बलराम की भीत उठी।' पर तिवारी ने इस मजमून को मिटा दिया है। अब कहा जा रहा है, "तिवारी के उत्तराधिकारी रामनरेश यादव भी बन सकते हैं। बलराम सिंह से कांग्रेस संभल नहीं रही, उसे संभालने के लिए वीरबहादुर सिंह ज्यादा उपयुक्त होंगे।" यह है, तिवारी का एक तीर से दो शिकार।

—रामपाल सिंह

कलह और चुनाव

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं की आपसी लागडांट का असर चुनाव पर पड़ना लाजिमी है। लगभग १५ व २० वर्ष बाद प्रदेश में स्थानीय निकायों और जिला परिषदों के चुनाव हुए। इन पर कांग्रेस के अंतर्कलह की काली छाया कदम-कदम पर पड़ती नजर आयी।

वाराणसी के दो विरोधी नेता सुधाकर पांडे और बहूजी (चंद्रा त्रिपाठी) के बीच इस बार तालमेल हो गया, पर केंद्रीय मंत्री श्यामलाल यादव, प्रदेश के मंत्री लोकपति त्रिपाठी, श्रीनाथ सिंह और संकठा प्रसाद अपना-अपना फड जमाये बैठे थे। इस झगड़े में सुधाकर पांडे हारे और जीत हाथ लगी शराब के बड़े व्यापारी जवाहरलाल सेठ के। इंका नेताओं ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेसी जहाज को कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों ने लाख-लाख रुपये लेकर डुबा दिया।

जौनपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह को विद्रोही कांग्रेसी वीरेंद्र सिंह ने धूल चटा दी। तेज बहादुर सिंह के ऊपर सांसद कमला सिंह का बल था। प्रदेश के मंत्री अरुण सिंह मुन्ना को लगा कि पानी में रह कर मगर से बैर जैसी बात हो रही है। उन्होंने अपनी शक्ति वीरेंद्र सिंह के पीछे लगा दी। बाद में वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस से निलंबित किया गया, पर निलबन को निरस्त करते भी देर नहीं लगी।

जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी का सर्वसम्मत प्रत्याशी नामजद करना तय हुआ था। यह भी तय हुआ था कि किसी मंत्री, विधायक आदि के रिश्तेदार को प्रत्याशी नहीं बनाया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन गोरखपुर से हुआ जहां वीरबहादुर सिंह के भाई गुलाब सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री डा० अम्मार रिजवी और केंद्रीय मंत्री राजेंद्रकुमारी वाजपेयी के आशीर्वाद से कई अपराधों से संबद्ध रामगोपाल मिश्र सीतापुर जिला परिषद के अध्यक्ष बने। इन्हीं कांग्रेसी नेताओं के आशीर्वाद से ओमप्रकाश गुप्त ने सीतापुर नगरपालिका के अध्यक्ष की गद्दी संभाली। ये दोनों व्यक्ति अतीत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीनस्थ जेल में डाले गये थे। देवरिया में जिसे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, वह कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं रहा। उसके विरुद्ध हत्या के दो मामले दर्ज हैं। इससे सांसद रामनगीना मिश्र, सीपीएन सिंह और राजमंगल पांडे को क्षोभ हुआ। राजमंगल पांडे तो इतना बिगड़े कि कांग्रेस ही छोड़ गये।

बाराबंकी में मोहसिना किदवई के रवैये से क्षुब्ध इंकाजनों ने विपक्षी उम्मीदवार को चुनाव जिताया। देहरादून में केंद्रीय मंत्री ब्रह्मदत्त और प्रदेश के मंत्री गुलाब सिंह का झगड़ा खुलकर सामने आया। गाजीपुर में बच्चा पाठक के दबाव से जिला परिषद् अध्यक्ष पद के लिए मतदाताओं ने 'हेल्पर' की मदद से वोट डाले, तब जाकर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत सका।

मुरादाबाद में उम्मीदवार का चयन इतने उग्र विवाद का कारण बना कि गुलाम नबी आजाद और बलराम सिंह यादव जब मुरादाबाद पहुंचे, तब दोनों को अपमानित होना पड़ा। कानपुर में तो वोट खरीदने के काम में चार मंत्रियों—नरेंद्र सिंह, सुशीला रोहतगी, गोपीनाथ दीक्षित और हुकुम सिंह को लगाना पड़ा, तब कांग्रेस का उम्मीदवार महापौर का चुनाव जीत सका। कहा जाता है कि एक-एक वोट एक-एक लाख रुपये में घरीदा गया। गोरखपुर महानगरपालिका के महापौर पद पर कांग्रेसी उम्मीदवार वीरबहादुर के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक बल से ही पहुंच सका।

—लखनऊ ब्यूरो

पतन के मुहाने पर बिहार की नौकरशाही

आजादी के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अमरीका के फोर्ड फाउंडेशन के लोकप्रशासन के विशिष्ट ज्ञाता पालएपलबी को आमंत्रित किया था कि वे भारत की प्रशासनिक स्थिति के बारे में अध्ययन कर अपना मंतव्य दें। पालएपलबी ने प्रतिवेदन में लिखा कि बिहार इस देश का सबसे बेहतर प्रशासित प्रांत है। उसका मूल कारण यही था कि बिहार के नौकरशाहों ने केंद्रीय स्तर पर एक जमाने में अपना रुतबा कायम किया था, पर अब उसी बिहार की नौकरशाही व पुलिस में इतनी गिरावट क्यों आ गयी है? क्या इसके लिए बिहार के नौकरशाह जिम्मेदार हैं? बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की हुकूमत में नौकरशाही की क्या हालत है? प्रस्तुत है, बिहार की चरमरायी हुई नौकरशाही की पतन-गाथा :

नये-नये मुख्यमंत्री बने सत्येंद्र नारायण सिंह पटना के बोरिंग रोड स्थित अपने निजी आवास पर दरबार लगाकर लोगों की बातें सुन ही रहे थे कि एक काली अम्बेसडर उस भीड़ को चीरती हुई एक धचके के साथ अंदर घुसी। वहां मौजूद सारे पुलिसकर्मी एकबारगी सावधान की मुद्रा में आ गये। इस अम्बेसडर में बैठे थे बिहार के पुलिस महानिदेशक जेएम कुरैशी। समर्थकों के बीच रेलमपेल में फंसे सत्येंद्र नारायण सिंह को जब उनके एक अनुचर ने जाकर बताया कि पुलिस महानिदेशक तशरीफ लाये हैं, तो भीड़ को तेजी से झटकते हुए सत्येंद्र नारायण सिंह अपने ड्राइंगरूम की तरफ बढ़े और पलटकर अपने अनुचर को आदेश दिया कि पुलिस महानिदेशक को वह फौरन अंदर लिवा लाये। बहरहाल, कुरैशी जब सिंह के सम्मुख हुए, तो कुछ ही पल की बातचीत के बाद स्थिति थोड़ी असहज हो गयी। फिर कुरैशी अपनी अम्बेसडर में बैठकर तुरंत वापस लौट गये। दरअसल, कुरैशी सत्येंद्र नारायण सिंह से हमेशा के लिए विदा लेने आये थे। सत्येंद्र नारायण सिंह ने उन्हें समझाने की हरसंभव कोशिश की कि वे कम-से-कम एक माह के लिए ही सही, अपने पद पर रुक जायें, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने के ठीक अगले ही दिन वे अगर पदत्याग कर पटना से कूच कर जाते हैं, तो बाहर तरह-तरह की भ्रांतियां फैलेंगी जिससे प्रशासन पर काफी असर पड़ेगा। पर सत्येंद्र नारायण सिंह के लाख समझाने के बावजूद कुरैशी अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था कि वे पारिवारिक कारणों से बहुत पहले से ही यहां से जाने का मन बना चुके थे और अब तो एक पल भी रुकने की स्थिति में वे नहीं हैं। कुरैशी की पारिवारिक परेशानी का यह तर्क भले ही अपनी जगह सही रहा हो, पर बिहार से वापस जाने का जो मुहूर्त उन्होंने चुना था, वह उचित नहीं था। क्योंकि लोग यह समझते थे कि आजाद गये, इसलिए कुरैशी भी जा रहे हैं। बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी 'माया' से कहते हैं, "बिहार में हर बार सत्ता-परिवर्तन के साथ पुलिस महानिदेशक व मुख्यसचिव का बदला जाना बिलकुल तय रहता है। इसलिए उस संभावित झटके से बचने के लिए कुरैशी ने एहतियात के तौर पर पहले ही जाने की जिद बांध ली।" वाकई जिस दिन मुख्यमंत्री पद से भागवत झा आजाद के इस्तीफे की खबर अखबारों के पहले पन्ने पर सुर्खियों में थी, ठीक उसी के समानांतर पुलिस महानिदेशक कुरैशी के पद त्यागने की खबर भी मोटे अक्षरों में छपी थी। दरअसल, जिस दिन आजाद राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को इस्तीफा देने गये, उससे पहले ही कुरैशी अपनी लंबी छुट्टी पर जाने का आवेदन लेकर पहुंच चुके थे। आजाद ने उसे तत्क्षण स्वीकृत करते हुए उसी आवेदन पर यह भी आदेश कर दिया कि कुरैशी की जगह पुलिस महानिदशक (कार्मिक) विजयानंद पांडेय अगली व्यवस्था तक के लिए कामकाज देखेंगे।

क्या हटेंगे ?
अरुण पाठक

इज्जत से हटे :
एसके मुखर्जी

२ मार्च, १९८८ से भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के निदेशक पद पर कार्यरत मध्य प्रदेश कैडर के चर्चित पुलिस अधिकारी कुरैशी को जब आजाद ने बिहार के पुलिस महानिदेशक पद पर बिठाया था, तो बिहार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में उसी समय काफी रोष पैदा हुआ था। दररअसल, बिहार के पुलिस अधिकारी इस बात से खिन्न थे कि उनके सिर पर किसी दूसरे प्रांत का पुलिस अधिकारी बिहार में पुलिस का प्रधान बनकर इससे पूर्व नहीं आया था। पर मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर आजाद का यह पहला अहम फैसला था, इसलिए कुरैशी के विरुद्ध उठा स्वर जोर नहीं पकड़ सका। फिर भी १९५६ बैच के आईपीएस कुरैशी को पुलिस महानिदेशक बनाये जाने की वजह से रुष्ट पुलिस अधिकारियों को शांत कराने के लिए बिहार के तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आजाद ने पुलिस महानिदेशक का दर्जा भी दिया। बिंदेश्वरी दुबे के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस महानिदेशक बने जिन सत्यनारायण राय को हटाकर कुरैशी को काबिज कराया गया था, उन्हें अग्निशामक सेवा और गृह रक्षावाहिनी का आरक्षी महानिदेशक बनाकर शंट कर दिया गया। पर बनवास का ऐसा दुर्दिन सिर्फ सत्यनारायण राय को ही भोगना पड़ा हो, ऐसा नहीं था। बिंदेश्वरी दुबे के राज में २२ जून, १९८७ को पुलिस महानिदेशक पद से शशिभूषण सहाय को हटाकर जब सत्यनारायण राय को लाया गया था, उस समय शशिभूषण सहाय के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ था। पुलिस महानिदेशक पद से हटाये जाने के बाद शशिभूषण को युवा कल्याण विभाग के तहत राज्य खेल प्राधिकरण में महानिदेशक सह परामर्शी का महत्वहीन पद दिया गया। सो उस समय पुलिस महकमे में यह बात हास-परिहास के रूप में कही जाती थी कि बेचारे सहाय को खेलने-कूदने के लिए छोड़ दिया गया है। बिहार की पुलिस में उच्च स्तर पर यह सब राजनीतिक खेल नया नहीं है। आजादी के बाद से ही राजनीति और जातीय समीकरण ने बिहार की पुलिस को आक्रात करना शुरू कर दिया था और इस तरह बिहार पुलिस का यह पतन पिछले चार दशकों में अत्यंत क्रमबद्ध ढंग से हुआ।

पतन की शुरुआत : यह किस्सा सन १९५० का है। उन दिनों अब्दुल फजल हमीद बिहार के पुलिस महानिरीक्षक हुआ करते थे। हमीद पक्के उसूलोंवाले पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने राजनीतिज्ञों के रहमोकरम पर काम करना कभी गवारा नहीं किया। आखिरकार एक ऐसा समय भी आया कि हमीद का तेवर राजनीतिज्ञों के लिए बिलकुल असहनीय बन गया। पर उन दिनों क्योंकि

राजनीतिज्ञों में थोड़ी-बहुत मर्यादा शेष थी, इसलिए आज के दिनों की भांति हमीद को पुलिस महानिरीक्षक पद से हटाया तो नहीं गया, पर उन्हें अपनी कुरसी पर पूरी तह पंगु बनाकर जरूर रख दिया गया। हमीद को कतरने के लिए ही एक दूसरे दिग्गज आईपीएस अधिकारी एकेपी सिन्हा को हरसंभव अधिकार से पूरी तरह लैस कर सीआईडी के डीआईजी पद पर तैनात कर दिया गया था। पर जब हमीद इससे भी पूरी तरह लगाम में नहीं आ सके, तो बिहार में उसी समय पहली बार डीआईजी (प्रशासन) के पद का प्रावधान किया गया और उस पर एमके सिन्हा को मुस्तैद किया गया। एमके सिन्हा वरीयता क्रम में कई पुलिस अधिकारियों से पीछे थे, पर राजकृपा ने उन्हें बहुत जल्दी इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने में कामयाबी दिला दी। इस तरह पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल फजल हमीद के इर्द-गिर्द इतने कील-काटे लगा दिये गये कि उस समय के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमीद इस सबसे इतने त्रस्त थे कि इस पद पर अपने कार्यकाल के चार वर्षों के दौरान वे महज इस आशंका से कभी एक दिन के अवकाश पर भी कहीं नहीं गये कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में कोई घालमेल न हो जाये, जिससे उन्हें अपमानित होना पड़े। बहरहाल, हमीद के जमाने में बिहार पुलिस में उच्च स्तर पर जो गंदा खेल शुरू हुआ, वह बढ़ता ही गया।

१९५८ की एक और घटना काफी चर्चित रही, जब बिहार के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसपी वर्मा को ऐन उस समय केंद्र की सेवा में भेज दिया गया, जब वर्मा के बिहार में पुलिस महानिरीक्षक बनने का समय आ गया था। इस तरह पहले जो बातें दबे-ढके तरीके से होती थीं, वे धीरे-धीरे खुलकर होने लगीं। इसलिए १९७१ में पुलिस महानिरीक्षक पद से टी नाथ को अपमानजनक स्थिति में हटाया गया। वजह सिर्फ यह थी कि नाथ राजनीतिज्ञों के इशारे पर आंख मूदकर चलने को राजी नहीं हुए थे। बहरहाल, बाद में डा० जगन्नाथ मिश्र जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनके समय भी पुलिस में यही खेल चला। जगन्नाथ मिश्र ने शुरुआत में एपी मिश्र को पुलिस महानिरीक्षक तथा राजेश्वर लाल को निगरानी महानिरीक्षक के पद पर बिठाया। पर थोड़े ही दिनों बाद जगन्नाथ मिश्र को इस बात का इलहाम हुआ कि एपी मिश्र को पुलिस महानिरीक्षक बनाकर उन्होंने गलती की, क्योंकि एपी मिश्र कायदे-कानून की बात ज्यादा कर रहे थे। आखिरकार एपी मिश्र को पुलिस महानिरीक्षक पद से जाना पड़ा और उनकी जगह आ गये निगरानी महानिरीक्षक राजेश्वर लाल। राजेश्वर लाल राजनीतिक तिकड़मों में माहिर थे, इसलिए राजनीतिक जोड़-तोड़ कर वे पुलिस महानिरीक्षक तो बने ही, अवकाश ग्रहण करने के बाद तो वे सक्रिय राजनीति में ही आ गये। संप्रति वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। पर आपातकाल के बाद जब डा० जगन्नाथ मिश्र की सत्ता का पतन हुआ और जनता सरकार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने राजेश्वर लाल को हटाकर, एपी मिश्र को पुलिस महानिरीक्षक बना दिया। फिर एपी मिश्र के रिटायर होने के बाद ही राजेश्वर लाल पुलिस महानिरीक्षक बन सके। पर कर्पूरी ठाकुर को हटाकर जब रामसुंदर दास १९७९ में मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक पद से राजेश्वर लाल की छुट्टी कर दी। फिर १९८० में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी और डा० जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्र ने बिहार पुलिस की भूमिहार लाबी को शुरू में इस गुस्से में दबोचा, क्योंकि वे जनता राज में अपने खिलाफ इस लाबी की गतिविधियों से काफी क्षुब्ध थे। इसी गुस्से के तहत बिहार पुलिस की भूमिहार लाबी के कड़े विरोध के बावजूद जगन्नाथ मिश्र ने फजल अहमद को पुलिस महानिरीक्षक की गद्दी सौंप दी।

अनुशासन में कमी आयी है: आरसी अरोड़ा

हरिजन अफसर उपेक्षित हैं: मैकू राम

एक और कुचक्र: बाद के दिनों में पुलिस महानिरीक्षक की औकात को कम करने के लिए एक और नायाब कुचक्र रचा गया और वह था—आरक्षी महानिरीक्षक (विधि-व्यवस्था) के नये पद का सृजन। बिंदेश्वरी दुबे ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इस पद का सृजन किया और इस जगह पर बिठाये गये रांची के तत्कालीन क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक ललितविजय सिंह। इस तरह नये पदाधिकारी के साथ ललितविजय सिंह के पुलिस मुख्यालय में आगमन से पुलिस महानिदेशक शशिभूषण सहाय की सांसत हो गयी। लिहाजा, भूमिहार व कायस्थ लाबी में जमकर टकराव शुरू हुआ। इस नये पद के सृजन से पुलिस महानिदेशक का सीधा संबंध अपने मातहत अधिकारियों से पहले जैसा नहीं रह गया। बिहार पुलिस में भूमिहार, कायस्थ तथा ब्राह्मण लाबी सबसे ज्यादा सक्रिय है। भूमिहार व कायस्थ लाबी में अकसर टकराव चलता रहता है और ब्राह्मण लाबी अपने लाभ की संभावनाओं के हिसाब से कभी कायस्थ, तो कभी भूमिहार लाबी का साथ देती रही है। शशिभूषण सहाय वरीयता के कारण पुलिस महानिदेशक बने थे, पर औरंगाबाद के दलेलचक बघौरा नरसंहार के बाद भूमिहार लाबी सहाय को अपदस्थ कराने में कारगर हो गयी।

इस तरह कई वरीय पुलिस अधिकारियों को लांघते हुए सत्यनारायण राय बिंदेश्वरी दुबे के राज में पुलिस महानिदेशक की कुरसी पाने में सफल हो गये। सत्यनारायण राय के इस तरह पुलिस महानिदेशक बनने से नाराज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खुश करने के लिए बिंदेश्वरी दुबे ने पुलिस महानिदेशक स्तर के चार और पद सृजित किये जिन पर हारुन रशीद, हरिहर प्रसाद सिंह, एएमपी वर्मा तथा शशिभूषण सहाय को बिठाया। पर जब भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बनकर आये, तो पहला काम उन्होंने सत्यनारायण राय को हटाने का और कुरैशी को बिठाने का किया। रामाश्रय प्रसाद सिंह को पहले ही आजाद ने अपने मंत्रिमंडल से दरकिनार कर दिया था और फिर सत्यनारायण राय के हटाये जाने से बिहार राजनीति व पुलिस की भूमिहार लाबी घायल गुस्से में थी।

बहरहाल, आजाद के सत्ताच्युत होने के बाद कुरैशी को भी शायद ऐसी ही आशंका हुई कि बदली हुई सत्ता में उनके लिए भी पराभव की स्थिति न पैदा हो जाये। पर कुरैशी इस बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सशंकित थे। कुरैशी से उस दिन की अपनी विफल वार्ता के बाद भी सत्येंद्र नारायण सिंह कुरैशी को टिकाये रखने के लिए परेशान थे। इसलिए कुरैशी जब उस दिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर चले गये थे, उसके तत्काल बाद सत्येंद्र नारायण सिंह ने अपने एक अत्यंत विश्वासपात्र वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार आयुक्त आरसी अरोड़ा को खास हिदायत के साथ कुरैशी के पास भेजा कि बिहार में कुछ ही दिनों के लिए कुरैशी को रुकने के लिए वे राजी कर लें। आरसी अरोड़ा 'माया' से कहते हैं, "मैंने कुरैशी को बहुत समझाया, पर पारिवारिक समस्या का हवाला देकर अंत तक वे नही ही माने।"

रिक्त पद: बहरहाल, कुरैशी के जाने के बाद पुलिस महानिदेशक का पद रिक्त है। यों पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) विजयानंद पांडेय उनका कामकाज देख रहे हैं, पर इस संबंध में अभी तक कोई सरकारी अधिसूचना तक नहीं जारी हुई। पुलिस महानिदेशक की जगह खाली होने से कई महत्वपूर्ण फैसले अधर में लटके हैं। यों नये पुलिस महानिदेशक के लिए जोर-शोर से मुहिम उसी दिन से तेज हो गयी है, जिस दिन से कुरैशी पटना से अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर गये हैं।

विजयानंद पांडेय तो इस पद की दावेदारी में शुरू से ही सक्रिय रहे, पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक पद पर कार्यरत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ललितविजय सिंह, विजिलेंस के पुलिस महानिरीक्षक एके चौधरी तथा सीआईडी के एडिशनल डीजी कृष्णप्रकाश की भी

लाबींग जोरो पर है। ललितविजय सिंह के विरोधी इस तर्क के साथ उनकी उम्मीदवारी काटते रहे हैं कि वे बस छह माह में ही अवकाश ग्रहण करनेवाले हैं, इसलिए इतनी अल्पावधि के लिए उनका पुलिस महानिदेशक बनना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। वहीं एके चौधरी के विरोधी इस तर्क के साथ शुरू से ही सक्रिय रहे हैं कि डा० जगन्नाथ मिश्र के संबंधी होने की वजह से चौधरी सत्येंद्र नारायण सिंह के लिए ग्राह्य नहीं हो सकते। कृष्णप्रकाश के संबंध में पुलिस महकमे में यह चर्चा गर्म थी कि कृष्णप्रकाश के संबंध सत्येंद्र नारायण सिंह से उन्हीं दिनों से हैं, जब वे गया के आरक्षी अधीक्षक हुआ करते थे। इसलिए कृष्णप्रकाश रेस में आगे निकल सकते हैं।

बहरहाल, सत्येंद्र नारायण सिंह द्वारा लगातार यह इत्मीनान दिलाये जाने के बावजूद कि वे कोई विशेष प्रशासनिक रद्दोबदल नहीं करेंगे, बिहार की नौकरशाही अनिश्चितता की स्थिति से उबर नहीं पा रही है। बात उसी दिन की है जिस दिन सत्येंद्र नारायण सिंह कुरैशी को मनाने में विफल रहे थे। उसी दोपहर प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी कि आजाद-राज में पुलिस महानिदेशक बने कुरैशी तो समझदारी दिखा कर खुद ही चले गये, पर आजाद-राज में अपने से २१ वरिष्ठ अधिकारियों को लांघकर मुख्य सचिव बने अरुण पाठक की छुट्टी वे कब करने जा रहे हैं? आखिरकार सत्येंद्र नारायण सिंह ने तिक्त होकर कहा, "मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही आप लोग अफसरों के बदले जाने की बात को बिलकुल पक्का मानकर क्यों चलने लगते हैं? नेताओं के साथ अफसरों को ब्रांड नहीं किया जाना चाहिए कि यह अफसर अमुक नेता का है और वह अफसर अमुक नेता का।"

सत्येंद्र नारायण सिंह जिस समय पत्रकारों के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उसके पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सरकार के विकास आयुक्त शंकर शरण गुलदस्ता लेकर वहां चहलकदमी करते देखे गये थे। शंकर शरण से सत्येंद्र नारायण सिंह के पुराने संबंध रहे हैं और उसी तरह राजस्व आयुक्त आरसी अरोड़ा से भी। अरोडा जिन दिनों गया के जिलाधिकारी थे, उसी समय से वे सत्येंद्र नारायण सिंह के काफी निकट हैं। उन दिनों गया, औरंगाबाद, नवादा और जहानाबाद को मिलाकर एक ही गया जिला था। कहते हैं, सत्येंद्र नारायण सिंह से निकटता के कारण ही अरोड़ा वरीय होते हुए भी हर शासन में शंट रहे। वर्तमान मुख्यसचिव अरुण पाठक ही वरीयता के क्रम में उनसे पंद्रह नंबर नीचे हैं। एक आईएएस अधिकारी 'माया' से कहते हैं, "शायद सत्येंद्र सिंह अपने इस विश्वासपात्र अधिकारी को उनके कारण मिली अब तक की उपेक्षा का प्रतिकार करना चाहें। ऐसा करना भी चाहिए। जब किसी राजनेता के कारण किसी वरिष्ठ अधिकारी को उपेक्षा व अपमान सहना पड़ता है, तो उस राजनेता के बेहतर दिनों में उसे दोगुना अवसर भी मिलना चाहिए।" सत्येंद्र नारायण सिंह के स्नेहभाजन शंकर शरण को भी कम अपमान पिछले दिनों नहीं झेलना पड़ा है। अरुण पाठक के हाथों अपनी बेइज्जती का दंश वे शायद ही भूल पाये हों, जब आजाद-राज में अरुण पाठक ने विकास आयुक्त के रूप में उन्हें विफल साबित करवाते हुए विकास संबंधी मामलों के कार्यान्वयन का जिम्मा स्वयं ले लिया था। इस झटके से आहत शंकर शरण ने अपने को पद से मुक्त किये जाने की जब पेशकश कर दी थी, तो उनका खोया अधिकार उन्हें फिर से मिल पाया। बहरहाल, किंग जार्ज एवेन्यू स्थित पटना सचिवालय पर अटकलों के बादल मंडरा रहे हैं कि मुख्यसचिव पद से अरुण पाठक को कब रुखसत किया जाता है और वे कहां जाते हैं। आजाद ने जब मुख्यसचिव पद से आर श्रीनिवासन को हटाकर २१ अधिकारियों को सुपरसीड कराते हुए अरुण पाठक को मुख्य सचिव पद सौंपा था, उस समय श्रीनिवासन को सजा के तौर पर एक सदस्यीय बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन कर उसका अध्यक्ष बनाया था। अरुण पाठक के कारण श्रीनिवासन को जो दंड भुगतना पड़ा, वैसा ही दंड श्रीनिवासन की वजह से उनसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीआर बैद्यनाथन को भी भुगतना पड़ा था। बिंदेश्वरी दुबे के राज में जब केके श्रीवास्तव मुख्यसचिव पद से रिटायर हुए, तो वरीयता के क्रम में सीआर बैद्यनाथन का नाम सबसे ऊपर था। बैद्यनाथन एक योग्य अधिकारी के रूप में भी ख्यात थे, पर श्रीनिवासन को मुख्यसचिव बनाने के लिए वरीय बैद्यनाथन को शंट करते हुए स्थानिक पदाधिकारी (बिहार के विश्वविद्यालय) बनाकर दिल्ली भेज दिया गया था। इसलिए इस कटु परंपरा के तहत क्या अरुण पाठक भी हाशिये पर फेंक दिये जायेंगे? अरुण पाठक 'माया' से कहते हैं, "यह तो सौ फीसदी मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। भला मैं इसमें क्या कह सकता हूं?" अरुण पाठक का यह कथन सही है। एक मुख्यमंत्री की इच्छा से वे मुख्यसचिव बने, तो दूसरे की इच्छा से जा भी सकते हैं। आजादी के बाद से अब तक मुख्यसचिव पद पर यहां नियुक्ति व बर्खास्तगी इसी तरह होती रही है।

गुमनामी का दौर: किशोर कुणाल

नये शिकार: जेएम कुरैशी

१९४८ की बात है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डा० श्रीकृष्ण सिंह ने चार वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज करते हुए जब एलपी सिंह को बिहार का मुख्यसचिव बना दिया था, तो बिहार की नौकरशाही में उस समय भी बावेला मचा था। दिल्ली की वसंत-विहार कालोनी में अवकाश का जीवन व्यतीत कर रहे एलपी सिंह उस कटु प्रसंग को याद करते हुए 'माया' से कहते हैं, "मैंने श्रीबाबू (डा० श्रीकृष्ण सिंह) से जाकर कहा कि बेवजह मुझसे चार वरीय अफसरों को अनदेखा कर आपने मुझे मुख्यसचिव बना दिया है। हालांकि उन दिनों कमिश्नर व मुख्यसचिव का वेतन एक जैसा ही था, इसलिए आर्थिक घाटे की बात तो नहीं थी। पर प्रशासन में मुख्यसचिव का पद तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता ही है। श्री बाबू ने मुझसे कहा कि प्रशासन के हित में जो मैंने ठीक समझा, वह किया। आप किसी विवाद की चिंता किये बगैर अपना काम करें।" बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार आयुक्त आरसी अरोड़ा 'माया' से कहते हैं, "चार-पांच अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को मुख्यसचिव पद के लिए चुना जाना अन्यायपूर्ण नहीं। पर सीधे २०-२१ अफसरों को पीछे धकेल कर किसी को मुख्यसचिव बना दिया जाना अवश्य अन्यायपूर्ण है।" बहरहाल, डा० श्रीकृष्ण सिंह के समय में १९४८ से १९५६ तक मुख्यसचिव पद पर कार्य करने के बाद एलपी सिंह केंद्र की सेवा में भेज दिये गये और फिर उनकी जगह आये एमएस राव। डा० श्रीकृष्ण सिंह के बाद पंडित विनोदानंद झा मुख्यमंत्री पद पर आ चुके थे और शुरू में ही राव से उनका छत्तीस का रिश्ता हो गया था। राव एक कर्तव्यनिष्ठ व सख्त अफसर थे। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के मुताबिक एक बार एमएस राव ने कुछ अफसरों के तबादले किये। पंडित विनोदानंद झा ने राव महाशय को बुलाकर पूछा कि जिन अफसरों के तबादले उन्होंने किये हैं, क्या उन सबकी जाति से वे वाकिफ हैं? राव ने कहा कि वे अपने अफसरों की जाति नहीं, कार्यक्षमता को जानते हैं। अफसरों की जाति जानना न उन्होंने कभी जरूरी समझा है, न जानने की कभी जरूरत ही महसूस करेंगे। राव का यही कथन उनके पतन की खाई खोद गया। लिहाजा, उन्हें अपमानित करने का दौर शुरू हो गया। राव को औकात में लाने के लिए ही एसजे मजूमदार को अतिरिक्त मुख्यसचिव बनाकर राव की पूरी तरह उपेक्षा की जाने लगी। राव अब बस नाम के लिए ही मुख्यसचिव रह गये थे। आखिरकार उन्हें मुख्यसचिव पद से हटाकर हिंदुस्तान स्टील में डायरेक्टर पर्सनल के पद पर भेज दिया गया। फिर राव की जगह एसजे मजूमदार मुख्यसचिव बना दिये गये। मजूमदार राजनीतिज्ञों का दरबार लगाने में माहिर थे। राजनीतिक जोड़-

तोड़ में भी उनका कोई सानी नहीं था। आज जब बिहार में नौकरशाही के पतन पर कई वरिष्ठ नौकरशाह दृष्टिपात करते हैं, तो वे मानते हैं कि पतन की शुरुआत मजूमदार के समय से ही हुई। पर मुख्यसचिव पद पर जिस तरह जोड़-तोड़ कर मजूमदार काबिज हुए थे, उसी तरह इस पद से उनकी दुखद विदाई भी हुई। कृष्णवल्लभ सहाय जब बिहार के मुख्यमत्री बने, तो मजूमदार को हटाकर 'दिल्ली मिल्क सप्लाई कार्पोरेशन' के महाप्रबंधक के प्रभार में भेज दिया गया। एक आईएएस अधिकारी उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय हंसी में यह कहावत प्रचलित थी कि बिहार के मुख्यसचिव पद से हटाकर मजूमदार सीधे दिल्ली के 'हेड ग्वाला' बना दिये गये। बाद के अधिकांश मुख्य सचिवों की भी वही दुर्गति हुई। डा० जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान १९८२ में मुख्यसचिव बने एसके मुखर्जी 'माया' से कहते हैं, "जब मैं अपने पद से रिटायर कर गया, ठीक उसकी अगली सुबह एक पर्व मुख्यसचिव तथा दो पूर्व पुलिस महानिदेशक मेरे पास बधाई देने आये और कहा कि मिठाई खिलाइए, आप बाइज्जत मुख्यसचिव पद से रिटायर हो गये।" सचमुच बिहार में कोई मुख्यसचिव इज्जत से अपने पद से अवकाश ग्रहण कर ले, ऐसा कम ही हुआ है।

जातिवाद की घुसपैठ: रामसुंदर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्यसचिव रहे लक्ष्मेश्वर दयाल 'माया' से कहते हैं, "जब जनता सरकार बनी, तो उस समय आरपी खन्ना पहले से मुख्य सचिव थे। उन्हें यह कह कर हटा दिया गया कि वे कांग्रेसी सरकार के मुख्यसचिव रहे थे।" १९५१ बैच के आईएएस लक्ष्मेश्वर दयाल पुराने वक्त को याद करते हुए कहते हैं, "नौकरशाही में भी जातिवाद की घुसपैठ राजनेताओं ने करा दी। हरेक नेता अपनी जाति के अधिकारी से अपने लिए सिर से पांव तक प्रतिबद्ध रहने की उम्मीद करता था और आज तो यह सब खुलेआम है। पर मेरे विरुद्ध मेरी ही जाति के एक मंत्री ने एक बार मेरे सीआर में एक भयंकर टिप्पणी दर्ज कर दी थी। मैं उनके साथ सहकारिता सचिव था। कृष्णवल्लभ सहाय ने मेरे सीआर में लिखा कि ये एक योग्य अधिकारी हैं, पर ये सहयोग नहीं करते हैं। मैं इसका विभागीय स्तर पर ऐसा स्पष्टीकरण दे सकता था जिससे कृष्णवल्लभ सहाय परेशानी में पड़ सकते थे, पर मैं किसी विवाद को न्योता नहीं देना चाहता था। दुखद स्थिति केवल बिहार में है। पश्चिम बंगाल में मेरे एक मित्र एसवी कृष्णन कांग्रेस की सरकार में भी मुख्यसचिव रहे और सीपीएम की सरकार में भी, पर बिहार में हर राजनीतिक दल का अपना मुख्यसचिव होता है।"

राजनेताओं के साथ अपनी प्रतिबद्धता के कारण ही वर्तमान मुख्य सचिव अरुण पाठक बिहार के सर्वाधिक विवादास्पद नौकरशाह रहे हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण उन्हें जहां कड़ी उपेक्षा झेलनी पड़ी, वहीं नौकरशाही का सर्वोच्च पद बतौर पुरस्कार भी मिला। जिन दिनों डा० जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन दिनों अरुण पाठक उनके अतिविश्वस्त अधिकारियों में गिने जाते थे। जगन्नाथ मिश्र का ठप्पा लगे होने के कारण ही बिंदेश्वरी दुबे के कार्यकाल में अरुण पाठक को गर्दिश के कड़े दौर से गुजरना पड़ा था। दुबे-राज में अरुण पाठक को वित्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाकर संस्कृति एवं क्रीड़ा विभाग का सचिव बनाकर दंडित किया गया था। काफी पहले अरुण पाठक शिक्षा आयुक्त रह चुके थे जिसके अंतर्गत संस्कृति एवं क्रीड़ा विभाग भी शामिल था, पर शिक्षा विभाग से पृथक कर बनाये गये इस छोटे से महत्वहीन विभाग में वनवास काटने के लिए अरुण पाठक विवश थे।

दरअसल, वित्त सचिव के रूप में अरुण पाठक बिंदेश्वरी दुबे के लिए सिरदर्द बन चुके थे, क्योंकि दुबे के सभी वित्तीय फैसलों पर अरुण पाठक नियम के उल्लंघन की बात उठाकर अड़ंगा लगा देते थे।

बदहाल नौकरशाही: लक्ष्मेश्वर दयाल

पद से छुट्टी: आर श्रीनिवासन

वित्त सचिव के नाते अरुण पाठक ने यह मामला उठाया कि मार्च की शुरुआत में ही सरकारी कोष में जमा ७४५ करोड़ रुपए में से ६०० करोड़ रुपए बस एक माह में निकाल लिये जाने से इस मोटी राशि का सही इस्तेमाल प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए नहीं हो सका। पाठक ने सहकारिता विभाग की क्रय योजना में छह करोड़ की उपबंधित राशि को अचानक ३२ करोड़ कर दिये जाने पर भी घोर आपत्ति प्रकट की थी। इस तरह रोज की किच-किच से खीझकर बिंदेश्वरी दुबे ने अरुण पाठक को वित्त सचिव पद से हटाकर ही दम लिया। पर पाठक के गर्दिश के ये दिन उस समय छंट गये, जब बिंदेश्वरी दुबे की सरकार के पतन के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी पर भागवत झा आजाद काबिज हुए। बहरहाल, आजाद-राज में पाठक की मुख्यसचिव बनने की मुराद तो पूरी हो ही गयी, पर नौकरशाही में भीषण संक्रमण की स्थिति आ गयी। एक आईएएस अधिकारी 'माया' से कहते हैं कि अरुण पाठक के तमाम मातहत अधिकारी जो अरुण पाठक से वरीय हैं, विभिन्न विभागों के प्रधान हैं। इन अधिकारियों ने कभी अरुण पाठक को मुख्यसचिव के रूप में मान्यता ही नहीं दी। पाठक द्वारा मुख्यसचिव की हैसियत से बुलायी गयी बैठकों में भी वे अधिकारी कभी शरीक तक नहीं हुए। जाहिर है नौकरशाही में मचे इस महाभारत के कारण मुख्य सचिव का किसी भी विभाग पर नियंत्रण नही रहा और किसी विभाग का एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं रहा। इस तरह की निरंकुशता का सीधा असर प्रदेश की विकास योजनाओं पर पड़ा।

आजादी के पश्चात पंडित नेहरू ने अमरीका के फोर्ड फाउंडेशन से लोकप्रशासन के विद्वान पालएपलबी को भारत की प्रशासनिक स्थिति के संबंध में अध्ययन कर प्रतिवेदन देने के लिए बुलाया था। पालएपलबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बिहार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रशासित प्रांत है। पर आज वही सर्वश्रेष्ठ प्रशासन पतन के गर्त में कैसे धंसा हुआ है? मुख्यसचिव अरुण पाठक 'माया' से कहते हैं, "सही मायने में यह पतन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के कारण आया बदलाव है। जहां तक यहां नौकरशाही पर राजनीतिक दबाव का प्रश्न है, तो यह महज एक भ्रांति है। इतने वर्षों की अपनी नौकरी में मुझे तो आज तक ऐसा महसूस नही हुआ। जब तक स्वयं कोई अधिकारी दबाव को न्योता नहीं देगा, तब तक यहा दबाव की कोई संभावना ही नहीं।" राजस्व आयुक्त आरसी अरोड़ा का भी मानना है कि अफसरों पर राजनीतिक दबाव उस रूप में नही है, जितना कि प्रचारित है। अरोड़ा 'माया' से कहते हैं, "३२ साल की नौकरी हो गयी मेरी, आज तक मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हां, अधिक-से-अधिक यह होता रहा है कि अगर कोई अफसर किसी राजनेता को सूट नहीं कर रहा है, तो उसका उस विभाग से तबादला कर दिया जाता है। पहले और आज में एक फर्क अवश्य आया है और वह यह कि पहले सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी ही राजनेताओं के सीधे संपर्क में रहते थे, लेकिन अब तो छोटे अधिकारी भी राजनेताओं के संपर्क में रहते हैं। इससे अनुशासन में कमी आयी है। छोटे अफसर की राजनेता के पास अच्छी पहुंच है, तो वहां उसका बड़ा अधिकारी दरकिनार हो जाता है।"अफसरों पर राजनीतिक दबाव के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय के संयुक्त सचिव निर्मलेंदु चटर्जी एक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, "१९४२ में एक भारतीय वाईए गोडबोले बिहार के मुख्य सचिव हुआ करते थे। एक बार की घटना है कि एक भारतीय जज कोर्ट जा रहे थे। रास्ते में कर्मचारी सड़क की सफाई कर रहे थे। उन अंग्रेज कर्मचारियों ने जज को पकड़कर सड़क साफ करने को कहा। जज ने अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार की शिकायत सरकार के पास भेजी। उन दिनों गवर्नर के पद पर थे ह्यूडो। वे बेहद सख्तमिजाज माने जाते थे और भारतीयों के प्रति

उनका रवैया भी अच्छा नहीं था। मुख्य सचिव गोडबोले ने गर्वनर ह्यूडो के पास जज के साथ हुई घटना का ब्योरा भेजते हुए अनुशंसा की कि उन कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर ने उत्तर में लिखा कि कोई बात नहीं, जज भारतीय थे। इस उत्तर पर मुख्य सचिव गोडबोले ने लिखा कि शायद भारतीयों के प्रति आपलोगों के इसी बर्ताव के कारण महात्मा गांधी अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते हैं। गोडबोले की इस टिप्पणी पर गवर्नर ने मात्र 'धन्यवाद!' लिखकर फाइल लौटा दी।" निर्मलेंदु चटर्जी 'माया' से कहते हैं कि यह प्रसंग साबित करता है कि ब्रिटिश राज में एक भारतीय अफसर ने सही बात के लिए किस सीमा तक दुस्साहस किया था। पर आज स्वयं आशंकाग्रस्त हो अफसर सही बात के लिए इस हद तक दुस्साहस का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वे यह कहकर अपनी जान छुड़ायें कि राजनीतिक दबाव के कारण वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 'माया' से कहते हैं कि कोई मंत्री किसी अफसर को यह नहीं कहता कि आप ऐसा ही नोट फाइल पर लिख दें। हमलोग चाहे किसी मामलें में नियम का हवाला देकर कड़ी प्रतिकूल टिप्पणी कर दें, मंत्री उसे अनदेखा कर अपनी तबीयत का आदेश आंख मूंद कर कर देते हैं। दरअसल, फाइल पर अनुकूल नोट देने के लिए मंत्री अफसर से कहने की जरूरत इसलिए नहीं समझते, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक राजनेताओं पर जितने भी जांच कमीशन बैठे—मसलन: चर्चित अय्यर कमीशन, मधोलकर कमीशन, अहमद कमीशन—उससे नेताओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा। लिहाजा, जांच कमीशनों व भ्रष्टाचार के आरोपों के भय से यहां के राजनेता पूरी तरह निर्द्वंद्व हैं, इसलिए अफसरों पर दबाव देने के बजाय सीधे स्वयं मनमाना आदेश कर देते हैं। वाकई यह व्याख्या बिहार के नौकरशाहों व राजनीतिज्ञों के बीच के अनूठे प्रशासनिक संबंध को स्पष्ट करती है। अय्यर कमीशन में तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्णवल्लभ सहाय से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह जो उन दिनों मंत्री थे, पर मनमाने ढंग से आदेश देने के अनगिनत मामले थे और साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के भी संगीन आरोप थे। अय्यर कमीशन की रिपोर्ट भी आ गयी, पर रिपोर्ट गतालखाते में चली गयी, किसी का बाल बांका तक नहीं हुआ। अय्यर कमीशन की रिपोर्ट में कृष्णवल्लभ सहाय वाले अध्याय में पृष्ठ संख्या ८० से ८६ तक नियुक्तियों, तबादलों व प्रोन्नति संबंधी अनियमितताओं के गंभीर आरोप दर्ज हैं, वहीं कमीशन की रिपोर्ट में सत्येंद्र नारायण सिंह से संबंधित अध्याय में पृष्ठ संख्या २६४ से २८७ तक सिंह द्वारा नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति व भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का उल्लेख है।

राजनेताओं के साथ आईएएस व आईपीएस अधिकारियों की अकसर ठनती रहती है। भोजपुर के जिलाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव जब केंद्रीय राज्यमंत्री केके तिवारी की बंदगी के लिए राजी नहीं हुए, तो उनका तबादला कर दिया गया। मनोज भोजपुर के जनप्रिय अधिकारी थे। लिहाजा, उनके स्थानांतरण के विरोध में भोजपुर से लेकर पटना तक जनप्रदर्शन हुआ, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मनोज को जाना ही पड़ा। यही स्थिति बिहार के बाबी कांड को लेकर चर्चित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की हुई। बाबी कांड के बाद कुणाल को बिलकुल गुमनामी के गर्त में धकेल दिया गया। फिर कभी उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौंपी गयी। यही हाल चर्चित आईपीएस अधिकारी डीएन गौतम का भी हुआ। बिहार राज्य वित्त निगम के अध्यक्ष जब कृष्णकांत सिंह थे, तो उनकी अपने प्रबंध निदेशक जीएस दत्त से ठन गयी। आखिरकार विवश होकर सरकार ने सिंह व दत्त दोनों को निगम से चलता कर दिया। आईपीएस अधिकारियों व राजनेताओं की मुठभेड़ भी बिहार में सुर्खी बनती रही है। डीआईजी शिवचंद्र झा ने १९८५ के मई माह में पुलिस महानिदेशक को एक रिपोर्ट दी कि मध्य बिहार में बढ़ती हिंसा के पीछे एक मंत्री का हाथ है। यह बात तूल पकड़ गयी और मंत्री रामाश्रय सिंह इस टिप्पणी के कारण विवाद के घेरे में आ गये। लिहाजा, शिवचंद्र झा की प्रोन्नति रोक दी गयी। जब शिवचंद्र ने मंत्री से खेद व्यक्त किया, तब जाकर उनकी प्रोन्नति हो पायी। सारण के निर्दलीय विधायक प्रभुनाथ सिंह ने तो सारण के आरक्षी अधीक्षक जेके खन्ना पर खुलेआम आरोप लगाया था कि खन्ना उनकी जान लेना चाहते हैं। आखिरकार खन्ना का तबादला वहां से कर दिया गया।

विवाद पहले भी हुआ था: एलपी सिंह

सत्ता बदलते ही पद से वंचित: सत्यनारायण राय

◆

क्या बिहार की नौकरशाही अपने पतन से उबर सकेगी? इसकी संभावना तो दूर-दूर तक फिलहाल दिखायी नहीं देती है।

◆

बिहार के हरिजन आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी भी पिछले कुछ दिनों से काफी मुखर हैं। हरिजन अधिकारियों के सवाल पर आरक्षी महानिरीक्षक मैकू राम अलख जगा रहे हैं। हरिजन अधिकारियों के हकों की रक्षा के लिए मैकू राम ने एक संगठन भी बना रखा है। मैकू कहते हैं, "बिहार में ३१ हरिजन आईएएस अधिकारी हैं तथा २३ आईपीएस अधिकारी। कुछ को छोड़ सभी उपेक्षित स्थिति में हैं। पूरे बिहार में आरक्षी अधीक्षक के पद पर मात्र चार हरिजन अधिकारी हैं। हमारी हालत तो बत्तीस दांतों के बीच जीभ-सरीखी है।"

क्या बिहार की नौकरशाही अपने पतन से उबर सकेगी? इसकी संभावना तो दूर-दूर तक फिलहाल दिखायी नहीं देती है। जिन दिनों लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय एक बार दिल्ली में वे वरिष्ठ अफसरों की एक बैठक को संबोधित करने गये। उस समय विदेश सचिव पद पर सीएस झा थे, गृह सचिव पद पर एलपी सिंह तथा प्रधानमंत्री के सचिव पद पर एलके झा। लालबहादुर शास्त्री ने उच्चाधिकारियों की बैठक में हंसते हुए कहा, "इस देश के प्रधानमंत्री का गला इन्हीं तीन बिहारी उच्चाधिकारियों के बीच फंसा है।" वाकई, एक वह भी समय था जब बिहार के नौकरशाहों का देश स्तर पर रुतबा था। शास्त्री के जमाने में ताकतवर प्रधानमंत्री सचिवालय था जिसके प्रधान एलकेझा थे। चंद्रप्रकाश भांभरी ने अपनी पुस्तक 'ब्यूरोक्रैसी एंड पालिटिक्स इन इंडिया' में लिखा है कि 'शीघ्र ही एलके झा सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर आ गये। चाहे वे सरकारी समितियां हों या शास्त्रीजी के नेतृत्व में विदेश जाने वाले शिष्ट मंडल हों या शास्त्री से मिलने वाले विदेशी मेहमानों की बैठक हो, झा सभी जगह मौजूद थे। महत्वपूर्ण विदेशी राजदूतों ने जो जल्दी ही सब कुछ ताड़ लिया, झा से मिलने जाने लगे और झा भी अपना हाथ-पांव फैलाते गये, चाहे वह विदेश नीति हो या आर्थिक मामले।' लालबहादुर शास्त्री के जमाने में केंद्रीय स्तर पर नौकरशाही ने जो अपना रुतबा कायम किया, वह बाद में श्रीमती गांधी के समय और मजबूत हुआ। इसके पीछे दिल्ली में जमे बिहारी नौकरशाहों की ही प्रारंभिक भूमिका थी।

पर अब? अतीत की ये गौरवशाली बातें नौकरशाही की मौजूदा दुर्दशा पर महज परदा डालने के लिए दुहरायी जाती हैं। बिहार में विगत कुछ वर्षों से आईएएस की प्रतियोगी परीक्षा में बिहारी लड़के ही देशस्तर पर अव्वल आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रशांत ने आईएएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उससे पूछा गया कि वह किस प्रांत की सेवा में जाना चाहेगा। उसने लिखकर दे दिया कि बिहार को छोड़ कर उसे किसी प्रांत में भेज दिया जाये।

—विकास कुमार झा

छाया: दीपक कुमार

Raymond
CEMENT

जब किसी निर्णय पर सालों-साल साथ निभाने की बात निर्भर हो तो ठोस प्रमाण उसमें मदद करते हैं

प्रमाण १ : गुणवत्ता
रेमण्ड का नाम ही सर्वोच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय है.

प्रमाण २ : मज़बूती
बी आइ एस के मानकों से निश्चय ही ज़्यादा 'कॉम्प्रेसिव' शक्ति.

प्रमाण ३ : ब्लेन
महीनतम ब्लेन के कारण अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मनचाही मज़बूती की गारंटी.

प्रमाण ४ : जमाव गुण
रेमण्ड सीमेंट पूर्ण जमाव का आश्वासन देता है क्योंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जमाव की अवधि बी आइ एस मानकों से बेहतर है.

प्रमाण ५ : विक्रेताओं का जाल
देशभर में रेमण्ड के अधिकृत विक्रेताओं का जाल शत प्रतिशत असली सीमेंट उपलब्ध कराता है.

प्रमाण ६ : पैकेजिंग
स्वचालित रोटरी पैकेजिंग मशीनों द्वारा सबसे मज़बूत प्लास्टिक और जूट की बोरियों में पैक याने निकाल लिए जाने का अंदेशा ही नहीं.

प्रमाण ७ : बचत
कोई अन्य सीमेंट हर बार इतने ठोस लाभों की गारंटी दे नहीं सकते.

प्रमाण ८ : हमारे कुछ ग्राहक,
एन टी पी सी, ऑयल इंडिया लि., भारतीय रेलवेज़, वायजैक स्टील प्लांट, ईस्ट इंडिया होटल्स लि., आइ टी सी लिमिटेड, वोल्टास लि., टाटा रोबिन्स फ्रेसर, निटको टाइल्स, अंसल हाउसिंग प्रा. लि., एस.आर.एफ. निप्पॉन डेनरो इस्पात लि. जी.ई.सी.

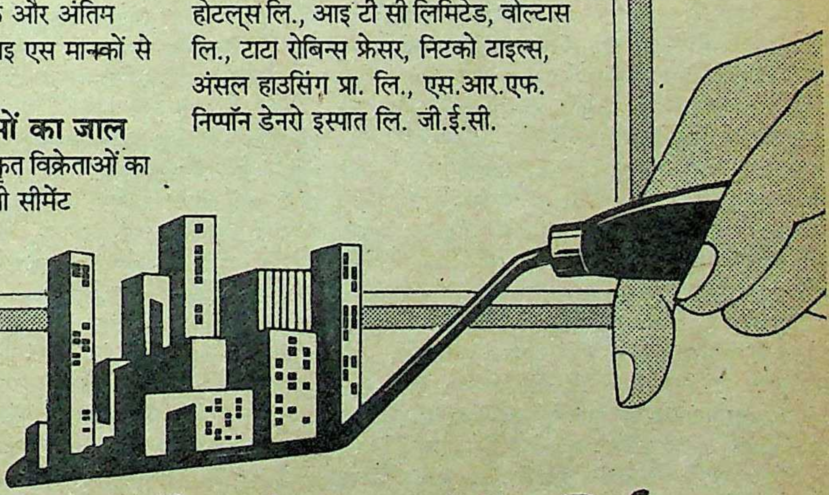

कैलाश सीमेंट : निर्माता

रेमण्ड

गुणवत्ता का दूसरा नाम.

पामेला

अदनान खशोगी के हथियार-व्यापार का सेक्स-सिक्का

वह दिन अब दूर नहीं रहा, जब पश्चिम में 'छिपी दहशत और खुली चर्चा' का विषय बनी भारत सुंदरी पामेला की खास, पक्की और जायकेदार कहानी का सबकुछ आपको पढ़ने के लिए सुलभ हो जायेगा। लंदन के अंग्रेजी दैनिक 'डेली मेल' ने इसका सर्वाधिकार (कापीराइट) खरीद लिया है और कहानी की कतिपय किस्तें प्रकाशित भी कर दी हैं। इंगलैंड और अमरीका के कई अन्य अखबारी प्रतिष्ठान भी इस मुहिम में जुटे हुए हैं। सब तो सब, हिंदी के कुछ प्रकाशक भी इस फिराक में हैं कि 'सेक्स और स्कैंडल की इस तूफानी कहानी' को किसी तरह छापकर कुछ धन बटोर लिया जाये। इस कहानी में कितने प्रामाणिक तथ्य हैं और कितने मनगढ़ंत, इसकी पड़ताल तो तथ्यों के विशेषज्ञ ही करेंगे, लेकिन पश्चिम में जहां एक तरफ इस कहानी के प्रति लोगों की उत्सुकता बेहद बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ बड़े-बड़े ताकतवर लोग अपने-अपने एकांत में थर्रा उठे हैं। कारण, उनकी शान-शौकत इस हसीन और बेवफा लड़की (पामेला) की मुट्ठी में आकर टूट रही है।

लंदन के अखबार 'डेली मेल' ने पामेला बोर्डेस के संस्मरण सिलसिलेवार छाप कर एक बार फिर दुनिया के लोगों का रुख इस खौफनाक सचाई की ओर मोड़ा है कि हथियार बाजार में खरीदार देशों के चोटी के अधिकारी व्यापारियों की इस 'सेक्स करेंसी' के जाल में फंस रहे हैं। १९ अप्रैल को पहली किस्त के साथ जो तस्वीर छपी उसमें पामेला के साथ अमरीकी संसद के अध्यक्ष (हाउस स्पीकर) जिम राइट हैं, जिनके कथित अनैतिक आचरण की इन दिनों जांच की जा रही है। यह तस्वीर कैपिटल हिल स्थित राइट के दफ्तर में, १९८३ में खींची गयी थी। तब राइट अमरीकी कांग्रेस के सदस्य थे। उन दिनों पामेला, बहुचर्चित भारतीय रहस्यवादी और तांत्रिक चंद्रा स्वामी का काम करती थी। स्वामी के वाशिंगटन में व्यापक व्यावसायिक सरोकार थे। उन्होंने ही पामेला से राइट की मुलाकात करवायी थी। 'डेली मेल' बताता है, "स्वामी के नजदीकी लोगों के मुताबिक उस मुलाकात में जिन विषयों पर बातचीत हुई, उनमें पामेला को अमरीकी प्रवासी होने के लिए आधिकारिक तौर पर एक 'ग्रीन कार्ड' परमिट दिलाने का प्रस्ताव भी था। यह तब की बात है जब पामेला, उसके ही शब्दों में, स्वामी के अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में सौदेबाजी के लिए 'यौन प्रलोभन' (सेक्स बेट) की भूमिका निभाती थी, हालांकि राइट को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस मुलाकात में स्वामी ने राइट को कुछ भेंट भी दी और पामेला की मदद के लिए उनसे अनुरोध भी किया। इस तस्वीर की एक प्रति उनके (राइट के) कर्मचारियों ने पामेला के पास भेजी थी। उस पर राइट के शुभकामनासहित हस्ताक्षर भी थे। बाद में वह और स्वामी जल्दबाजी में देश (अमरीका) से निकल भागे, क्योंकि व्यवसाय का एक सौदा कानूनी तौर पर खतरनाक बन चला था।"

पामेला बोर्डेस

पामेला, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में सौदेबाजी के लिए 'यौन प्रलोभन' की भूमिका निभाती थी।

अदनान खशोगी

चंद्रा स्वामी

जिस दिन यह कहानी छपी, उसी दिन संपर्क किये जाने पर राइट के एक प्रवक्ता ने कहा, "स्वामी और उनकी पार्टी, जिसमें पामेला सिंह (तब इसी नाम से जानी जाती थी वह) भी थी, के साथ मुलाकात हमें याद है, लेकिन हमें इसका स्मरण नहीं है कि ग्रीन कार्ड हासिल करने मे उसकी मदद के लिए कुछ किया गया।"

पामेला के संस्मरणों की इस कहानी में मशहूर शस्त्र-दलाल अदनान खशोगी, एक सऊदी शहजादे और लीबिया के कर्नल मोअम्मर गद्दाफी के एक शीर्षस्थ सहयोगी से जुड़े सेक्स के भयानक प्रकरण हैं। 'डेली मेल' ने पामेला का कथन उद्धृत करते हुए बताया है कि वह अरबपति सऊदी हथियार व्यवसायी खशोगी से १९८३ में पेरिस में मिली थी और खशोगी ने उसे 'जेट की गति से चलनेवाली कालगर्ल' बना दिया। पामेला बताती है, "मेरे हमबिस्तर होनेवालों में सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद भी हैं, जिनके साथ खशोगी हथियारों का एक बड़ा सौदा पटा रहा था।" जो सऊदी वीसा किसी गैरसऊदी कुंआरी औरत को आमतौर पर दिया ही नहीं जाता, वह पामेला को १९८३ में २४ घंटों के अंदर ही मिल गया और वह विमान से सऊदी अरब पहुंच गयी। 'डेली मेल' ने उस वीसा की तस्वीर के साथ-साथ पते-ठिकानों वाली उसकी पुस्तिका (ऐड्रेस बुक) के कुछ पन्ने भी छापे हैं, जिन पर खशोगी के पेरिस, केन्स, रियाद और (स्पेन के शहर) मारबला स्थित अड्डों के फोन नंबर भी दर्ज हैं।

पामेला बताती है कि १९८४ में वह अहमद गद्दाफी अल दियाम (जिसे 'डेली मेल' लीबिया के नेता का चचेरा भाई, लीबियाई गुप्तचर संगठन का सेकंड कमांडर और यूरोप में लीबिया का शीर्षस्थ हथियार-खरीदार मानता है) के निजी जेट से त्रिपोली भी गयी थी। वह कहती है, "चैंडली नाम के एक आदमी ने पेरिस में मुझे वीसा दिलाया और त्रिपोली में मैं अल दियाम की हमबिस्तर हुई।...अल दियाम ने मुझसे कौल कराया कि मैं कभी किसी को यह न बताऊं कि वह मुझे त्रिपोली ले आया है, क्योंकि यह एक सख्त मुस्लिम मुल्क है।...अल दियाम से मुझे अच्छी रकम मिली और मैं उसके संपर्क में तब तक रही, जब तक पिछले साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिसर्चर की नौकरी पाकर वहां (लंदन) न चली गयी।"

पामेला की इसी नौकरी ने ब्रिटिश प्रेस का ध्यान उसकी पिछली छवि और गतिविधि की ओर खींचा। यहीं से सवाल उठा, "लीबिया के उच्चस्तरीय व्यक्तियों से जुड़ी एक महिला को हाउस आफ कामंस में बेरोकटोक आने-जाने की छूट देकर क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है?" इसके साथ ही ब्रिटेन में सनसनी फैल गयी। २६ वर्षीय पामेला भागकर बाली द्वीप में जा छिपी। ब्रिटेन के रिपोर्टरों ने वहां भी उसे ढूंढ़ लिया और बड़ी-से-बड़ी रकम चुकाकर उसकी कहानी खरीदने की होड़ लगा दी।

५४ वर्षीय खशोगी को पिछले १८ अप्रैल को अमरीका के कहने पर स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका का आरोप था कि खशोगी ने सत्ता से हटाये गये फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांद मारकोस और उनकी पत्नी इमेलदा की जायदाद छिपाने में मदद की है। 'डेली मेल' खशोगी और पामेला पर तैयार अपनी पूरी सामग्री अमरीकी गुप्तचर एजेंसी 'फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन' के वाशिंगटन स्थित मुख्यालय को भेज रहा है। दैनिक का कहना है, "इस सुंदरी के साथ सेक्स-सहवास, खूंख्वार हथियार-व्यवसायियों और राष्ट्रों के बीच सौदा पटाने के लिए, 'हार्ड करेंसी' (अमरीकी डालर की तरह बेशकीमती, टिकाऊ, दुर्लभ मुद्रा) के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।"

—वशिष्ठ

आँखें खोल कर खरीदें
सिर्फ सर्वश्रेष्ठ ही खरीदें

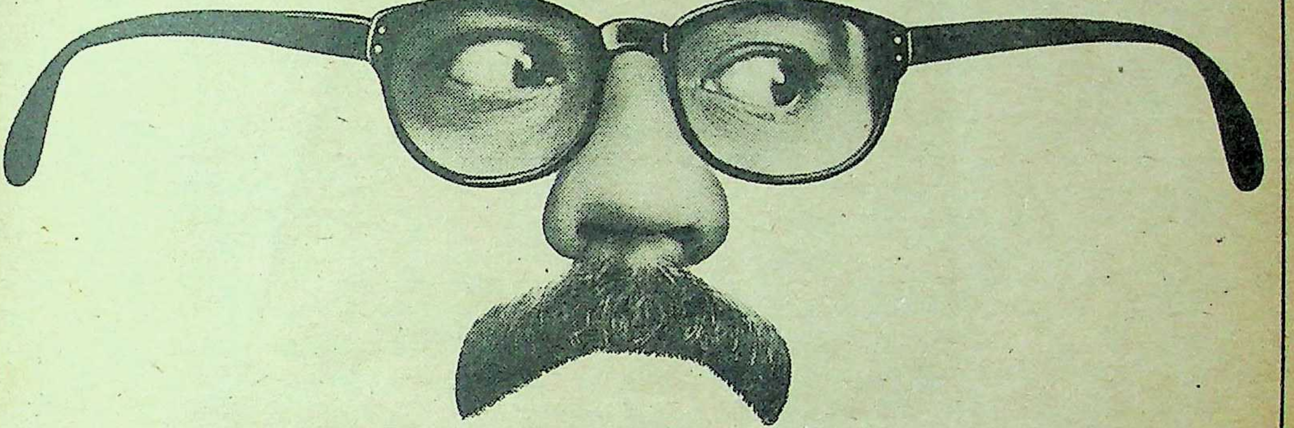

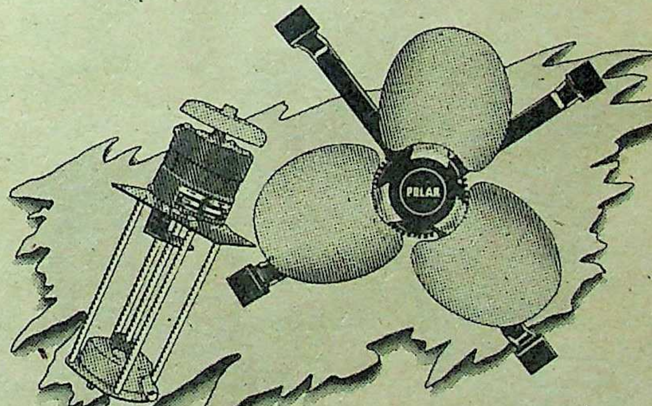

जरा सोचिए—आप डीलर के पास जाएं और सिर्फ "एक कूलर" की मांग करें बिना देखे कि उस कूलर में कौन सा कूलर पंखा व पम्प लगा है।

यह न जानते हुए कि शायद आप पाएं एक ऐसा कूलर जिसमें घटिया व पुरानी तकनीक से बना कूलर पंखा व पम्प लगा हो। सिवाय इसके कि आप आँखें खोलकर किसी एक नाम की मांग करें।

सिर्फ पोलर ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि पोलर कूलर पंखा और पम्प की मोटर पर चढ़ी बेक्टाल-2 की दोहरी परतें इसे जलने के खतरे से सुरक्षित रखती हैं और डाईनामिकली बेलेन्स ब्लेड अधिक हवा देते हैं।

इसलिए आप जब भी कूलर खरीदें आँखें बंद करके न खरीदें। विचार करें और पोलर ही खरीदें क्योंकि सिर्फ पोलर ही 100% भरोसेमंद है।

पोलर
कूलर पंखा & पम्प

सिर्फ सर्वश्रेष्ठ खरीदें - पोलर ही खरीदें

Pavitra/3291/2

जापान

भ्रष्टाचार का खमियाजा

आखिरकार, २५ अप्रैल को जापान के प्रधानमंत्री तथा गत ३४ वर्षों से जापान पर शासन कर रही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष नोबोरु ताकेशिता ने बजटोपरांत अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करके जापानी जनमत के आगे घुटने टेक दिये। असल में रिक्रूट कंपनी से लिये गये १५१० लाख येन यानी १० लाख डालरों ने जून, ८८ से जो हंगामा बरपा किया था, उसने ताकेशिता की राजनीतिक छवि धूलधूसरित कर दी थी। धीरे-धीरे स्थिति इतनी बिगड़ी कि फरवरी में विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा कराये गये जनमत-संग्रहों ने ताकेशिता के पैरों तले शीघ्र जमीन खिसकने के संकेत दिये, क्योंकि रिक्रूट घोटाले ने जनता में उनके प्रति ऐसे अविश्वास को जगह दी थी कि ६ प्रतिशत से अधिक मतदाता उनके पक्ष में नही रह गये थे। ऐसे में जरूरी था कि रिक्रूट से ली गयी रकम को स्वीकार करके पद से इस्तीफे की घोषणा की जाये, वरना ताकेशिता के साथ एलडीपी की स्थिति के भी खतरे में पड़ने का अंदेशा था। उल्लेखनीय है कि ताकेशिता पहले जापानी प्रधानमंत्री नहीं हैं, जिनके खिलाफ १९४७ में स्थापित विशेष जांच विभाग के टोक्यो पब्लिक प्रासिक्यूटर्स संभाग ने भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए जांच बिठायी है। ताकेशिता के पूर्व १९७६ में प्रधानमंत्री काकोई तनाका को अमरीकी वायुयान कंपनी 'लाकहीड' से २० लाख डालर लेने के जुर्म के तहत पद छोड़ना पड़ा था। तनाका से पूर्व १९५४ में प्रधानमंत्री शिगेरु योशिदा को मंत्रिमंडल सहित, जलपोत निर्माण कंपनी संबंधी आर्थिक घोटाले के कारण, इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं, १९४८ में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री हितोशी अशीदा को 'शोवा डी को' नामक दवाओं की कंपनी को गैरकानूनी वित्तीय सहायता देने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था।

भंडाफोड़ : प्रधानमंत्री नोबोरु ताकेशिता की छवि धूमिल करनेवाले रिक्रूट घोटाले का भंडाफोड़ तो जून १९८८ में ही हो गया था, जब जापान के प्रमुख समाचार पत्र 'असाही' ने कावासाकी के डिप्टी मेयर द्वारा रिक्रूट कंपनी से रिश्वत लेने के बारे में विस्तृत समाचार छापा था। किंतु 'असाही' की खोज रिक्रूट कंपनी से आर्थिक मदद ले रहे राजनीतिकों का भंडाफोड़ नही कर पायी थी। 'असाही' की रिपोर्ट को आधार बनाकर खोजबीन में जुट गये अन्य समाचार पत्रों ने एक महीने बाद ही ऐसे तथ्य जुटा दिये जो रिक्रूट कंपनी से राजनीतिकों के संबंधों को प्रकाश में लाये। इन रिपोर्टों में जापान के निवर्तमान प्रधानमंत्री यासुहिरो नकासोने को आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त बताया गया। चूंकि ताकेशिता नकासोने के कार्यकाल में एलडीपी के महासचिव तथा वित्तमंत्री थे, इसलिए शक की तेग उन पर भी लटकायी गयी। समाचार पत्रों ने यह संदेह जाहिर किया कि नकासोने ने अपने कार्यकाल में रिक्रूट कंपनी को अमरीकी सुपरकंप्यूटर खरीदने में मदद की। जाहिर है, ऐसी खबरों से राजनीतिक माहौल का गर्माना जरूरी था। हालांकि, ताकेशिता शुरू में इस बात से इनकार करते रहे कि रिक्रूट कंपनी से उनका अथवा उनके सहयोगियों का कोई संबंध है। किंतु दिसंबर, ८८ में ताकेशिता सरकार के वित्तमंत्री कीची मियाजावा ने जापानी राजनीति का यह कहकर नक्शा बदल दिया कि चूंकि रिक्रूट कंपनी से ली जानेवाली बड़ी रकम में उनका भी हाथ था, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा देते हैं। जापानी प्रेस तो इस दिन की राह देख ही रहा था।

जनमत को अपने खिलाफ होते देखकर प्रधानमंत्री ताकेशिता ने रिक्रूट कंपनी की सहयोगी कंपनी से १५१० लाख येन लेने की बात स्वीकार कर ली।

मियाजावा के इस्तीफे ने प्रेस के संदेह को मजबूत आधार दिया। नतीजतन, रिक्रूट की आर्थिक सहायता को लेकर प्रेस खोजबीन में जुट गया। दूसरी ओर, उच्चस्तरीय राजनीतिकों के भ्रष्टाचार की कलई खोलने का काम करनेवाले टोक्यो प्रासिक्यूशन विभाग ने भी फरवरी, ८९ में रिक्रूट के विरुद्ध जांच बिठा दी। जांच के दौरान रिक्रूट कंपनी के अध्यक्ष हिरमासा इजो की रिश्वतखोरी का राजफाश हुआ। साथ में रिक्रूट के चार और कार्यपालक अधिकारी मुजरिम पाये गये। इन अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद रिक्रूट घोटाले ने नया रंग ले लिया, क्योंकि जहां मियाजावा ने इस्तीफा देकर रिक्रूट घोटाले में राजनीतिकों के हाथ होने की पुष्टि की थी, वहीं रिक्रूट के अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने मामले को और संगीन बना दिया। नतीजतन, जापान का विपक्ष ताकेशिता का खुलकर विरोध करने लगा और जापान की संसद (डाइट) के समक्ष प्रदर्शनों और विरोधों का तांता बंध गया। ऐसे में जनमत को अपने खिलाफ होते देखकर प्रधानमंत्री ताकेशिता ने रिक्रूट कंपनी की सहयोगी कंपनी से १५१० लाख येन लेने की बात स्वीकार कर ली, किंतु उन्होंने यह भी कहा कि बदले में लाभ पहुंचाये बिना यदि राजनीतिक कार्यों के लिए उद्योगपतियों से दान स्वरूप धन लिया जाता है, तो वह जापान में गैरकानूनी नहीं, इसलिए इस्तीफा देने का सवाल नहीं पैदा होता। किंतु जापानी नियम यह भी कहता है कि राजनीतिक कार्यों हेतु बड़ी मात्रा में ली गयी रकम की जानकारी जनता को देना जरूरी है। जबकि रिक्रूट कंपनी से लिये गये धन की उस समय तक कोई चर्चा नहीं हुई, जब तक मामले ने गंभीर रुख अख्तियार नहीं किया। इसीलिए जापान का विपक्ष यह मानने पर मजबूर है कि ताकेशिता तथा उनके सहयोगियों ने रिक्रूट कंपनी से लिये गये धन की जानकारी सिर्फ इसलिए छिपाये रखी, क्योंकि उनके सहयोगी राजनीतिक मद में लिए गये दान का निजी उपयोग कर रहे थे। हालांकि, संसद में हंगामे के बीच ताकेशिता ने रिक्रूट से हासिल की गयी रकम और खर्च किये गये रुपयों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया।

विश्वास जीतने की कोशिश : ताकेशिता ने धन लेने की बात स्वीकार करके जनता का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश तो की, किंतु पद से चिपके रहने की बात को जनता ने पसंद नहीं किया। असाही टीवी द्वारा हाल में कराये गये जनमत संग्रह ने संकट को गहराते दिखाया, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रति सहानुभूति रखनेवालों का प्रतिशत ९ से घटकर ७.८ प्रर पहुंच गया। ऐसे में ताकेशिता के समक्ष इस्तीफे की घोषणा के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा था, एलडीपी की छवि का। एलडीपी के समक्ष आगामी जुलाई अथवा अगस्त में होनेवाले उच्च सदन (अपर हाउस) के चुनाव हैं। नतीजतन, पार्टी की छवि का खयाल करते हुए उन्होंने २५ अप्रैल को बजटोपरांत इस्तीफे की घोषणा कर दी। दूसरे ही दिन उनके सहायक इहही आओकी ने रिक्रूट से लेन-देन में अपना हाथ होने के कारण आत्महत्या कर ली।

बहरहाल, रिक्रूट घोटाले की असलियत का तो तभी पता चलेगा जब इस घोटाले की जांच पूरी होगी, किंतु जांच पूरी होने से पूर्व ही ताकेशिता ने इस्तीफे की घोषणा करके सत्तारूढ़ एलडीपी के संकट को टाल दिया है। सचाई जो भी हो, ताकेशिता के इस्तीफे की घोषणा, कीची मियाजावा का इस्तीफा और इहही आओकी की आत्महत्या उन देशों के राजनीतिकों के लिए एक सबक है, जहां एक जुर्म को छिपाने के लिए सैकड़ों जुर्म करने की परंपरा परवान चढ़ रही है। जापानी राजनीति में कम-से-कम यह विशेषता तो है कि राजनेता यदि बेईमानी करते हैं, तो उसे ईमानदारी से इकबाल कर लेते हैं।

—तारिक खान

नेल्को ब्लू डायमंड

ये देखा गया...

तुलना की गयी...

और इसे खरीदा गया...

अब, आपको किसका इंतज़ार है!

शानदार, लाजवाब नेल्को ब्लू डायमंड. रंगों का सर्वोत्कृष्ट दर्शन कराए. अपने नज़दीक के नेल्को विक्रेता के यहाँ देखिए. और सिर्फ़ अपनी आँखों पर भरोसा कीजिए.

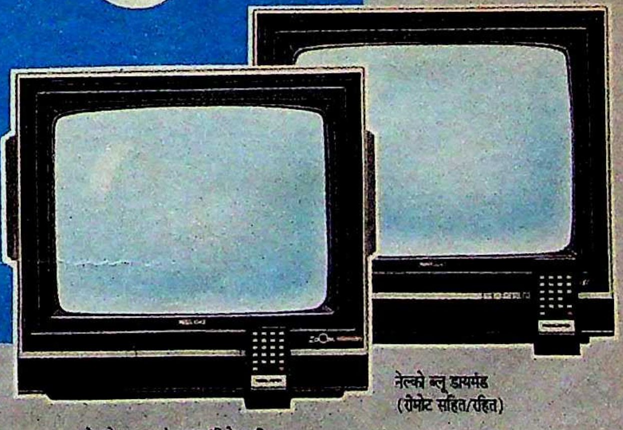

नेल्को ब्लू डायमंड
(रीमोट सहित/रहित)

नेल्को ब्लू डायमंड ज़ूम (रिमोट सहित)

MADISON-N-32-HN

टाटा उत्पादन

NELCO

ब्लू डायमंड

इससे बेहतर आप ख़रीद नहीं सकते.

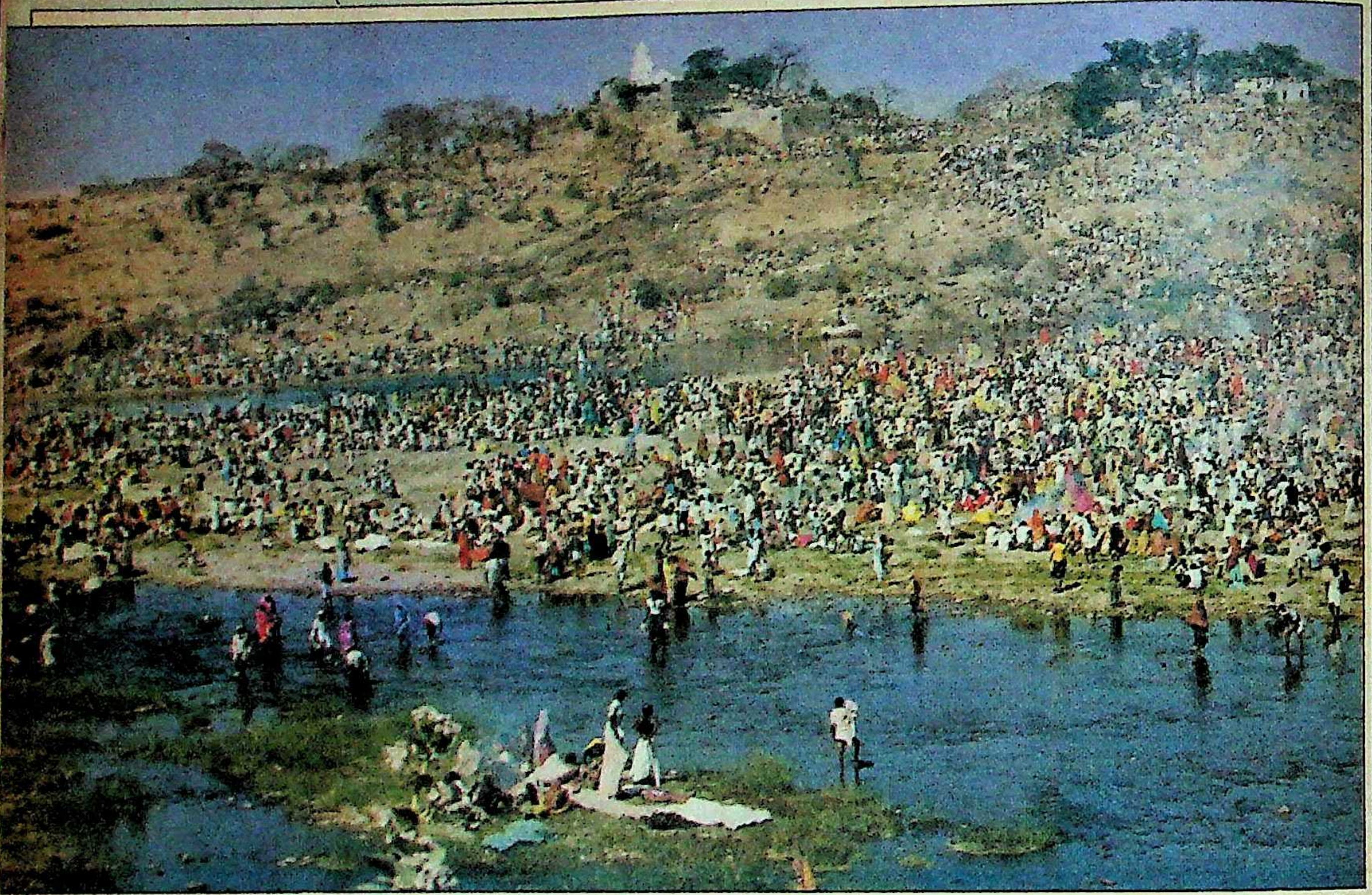

बेणेश्वर मेले का विहंगम दृश्य

छाया: प्रताप सिंह

पर्यटन व्यवसाय

खतरा सांस्कृतिक प्रदूषण का

भारत में जितने विदेशी पर्यटक आते हैं, उनमें से एक तिहाई पर्यटक राजस्थान जरूर जाते हैं, लेकिन सरकारी निगम उन्हें वे सुविधाएं क्यों नहीं दे पाते जो उन्हें निजी क्षेत्र के होटलों में मिलती हैं? सरकार पुरातत्व महत्व के स्थानों को निजी क्षेत्र के होटलों में क्यों तब्दील होने दे रही है?

यह निर्विवाद सत्य है कि राजस्थान अपनी वास्तुकला, संगीत एवं रंग बिरंगे मेलों त्यौहारों तथा लोक कलाओं के लिए पूरे विश्व में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इसी आकर्षण ने राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी आकर्षित किया है। सरकारी क्षेत्र में यह व्यवसाय एक अप्रैल, १९७९ से राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान होटल निगम चलाता है, तथा निजी क्षेत्र में ताज ग्रुप, क्लार्क ग्रुप और वेलकम ग्रुप अपने होटल चला रहे हैं। इन होटल समूहों में ताज ग्रूप के पांच सितारा होटल पांच हैं, जबकि क्लार्क और वेलकम के एक-एक होटल चल रहे हैं। ताज ग्रुप के पांच होटलों में से तीन जयपुर में स्थित हैं, एक उदयपुर में और एक सवाई माधोपुर में है। क्लार्क ग्रुप का होटल जयपुर में प्रतियोगिता में है, जबकि वेलकम ग्रुप के प्रबंध में चलनेवाला जयपुर का मानसिंह होटल उनसे वास्तविक मालिकों ने वापस ले लिया है। अब वेलकम ग्रुप जोधपुर के उमैद पैलेस के प्रबंध तक सीमित है।

व्यवसायीकरण: राजस्थान का पर्यटन व्यवसाय जिस तेजी से अधिकाधिक लाभ कमाने का धंधा बन रहा है, उसी गति से इन होटल समूहों में प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। इस प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप महलों, किलों और हवेलियों के मालिकों की बन तो आयी है, किंतु इस तरह के व्यवसायीकरण से राजस्थान की लोक संस्कृति एवं संरक्षित अवशेषों को जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे लगता है सरकार अभी बेखबर है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में देशी और विदेशी पर्यटकों की आमद में प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। मसलन १९७१ में आठ लाख अस्सी हजार देशी पर्यटक राजस्थान आये थे तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या ४२ हजार थी। यही संख्या १९८८ में बढ़कर क्रमशः ३४ लाख ९५ हजार व ३ लाख ६६ हजार हो गयी। पर्यटन के लिए आनेवाले देशी-विदेशी संपन्न पर्यटक पांच सितारा होटलों की सुविधा के इच्छुक होते हैं, उनका मानना है कि महलों और किलों का जो राजसी सुख होता है, उसे राजस्थान सरकार का पर्यटन विकास निगम उपलब्ध करा पाने में असफल रहा है।

पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के होटलों ने पर्यटक की इसी भावना को भुनाने का सफल प्रयास किया। हालांकि सभी ग्रूप अपने प्रयास में उतना सफल नहीं हैं, जितनी सफलता ताज ग्रप ने

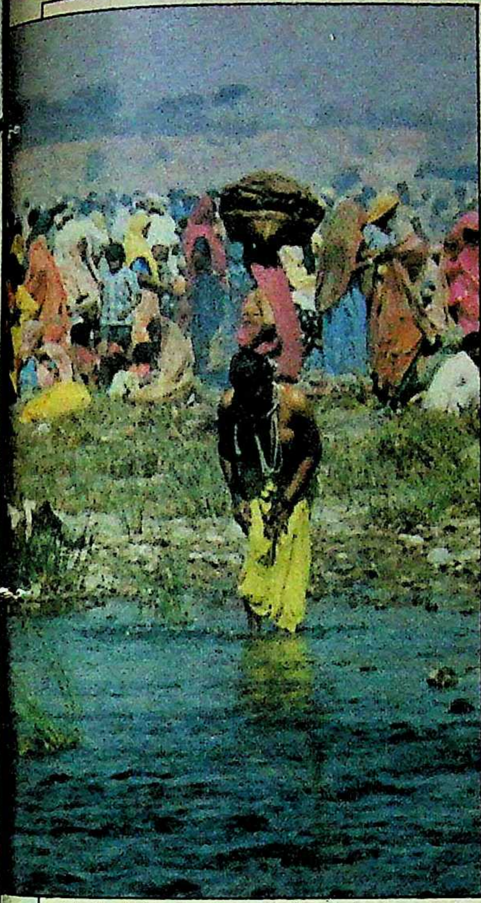

विदेशी कैमरे की नजर यहीं टिकती है

हासिल की है। इस ग्रुप ने जयपुर व उदयपुर के शाही महलों में वही रौनक कर दी है जो राजाओं के जमाने में हुआ करती थी। जयपुर के जयमहल पैलेस में ऐसा मुगल गार्डेन बनाया गया है जिसे यदि शहंशाह अकबर भी देखते, तो चकरा जाते।

दूसरी ओर राजस्थान पर्यटन विकास निगम अपने होटलों में पांच सितारा सुविधा और अपनेपन का वह अहसास देने में पूरी तरह असफल है जिसकी अपेक्षा शाही अवकाश बिताने की इच्छा के साथ राजस्थान आये पर्यटकों को होती है। यही वजह है सरकारी निगम के पीछे रह जाने की।

सांस्कृतिक नुकसान : स्थिति तो यह है कि राजस्थान के पर्यटन आकर्षण को भुनाने के लिए निजी क्षेत्र के वेलकम व ओबेराय ग्रुप ने ऐसे ऐतिहासिक किलों, महलों और हवेलियों को खरीदकर होटलों में बदलने का काम शुरू किया है, जो आज भी विवादास्पद रूप से निजी संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। विवादास्पद इन अर्थों में कि राज्य सरकार का पुरातत्व विभाग तो उस संपत्ति को राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान प्राचीन वास्तु अधिनियम, १९६१ की धारा-१७ के तहत संरक्षित घोषित कर चुका है, किंतु परंपरा से उत्तराधिकारी बने लोग इन्हें आज भी अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के २७ जिलों के ऐसे अवशेषों को संरक्षित घोषित करने में तो सरकार के पुरातत्व विभाग ने काफी फुरती दिखायी, लेकिन उन्हें खंडहर बनने से रोक पाने के लिए पुरातत्व विभाग के पास फंड नहीं है।

जयपुर से बीस किलोमीटर दूर ऐसा ही विवादास्पद 'नायला दुर्ग' है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि दुर्ग विशिष्ट निर्माण शैली के इतिहास का अंतिम नमूना है। इस दुर्ग को, भाजपा विधायक नाथूसिंह के अनुसार, नायला ठाकुर रामसिंह ने पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किये जाने के बावजूद ओबेराय ग्रुप के हाथ बेच दिया। जबकि पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों में यह दुर्ग ४ मई, १९८३ को संरक्षित घोषित हुआ है। ऐसे में दुर्ग की खरीद-फरोख्त आश्चर्य का विषय तो है ही।

दरअसल पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक अवशेषों को संरक्षित घोषित तो करता है, किंतु उनका रख-रखाव नहीं कर पाता। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब इस मसले पर चर्चा हुई, तो भाजपा विधायक नाथूसिंह का यही आरोप था। उनके अनुसार इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए एक किलोमीटर लंबे पहाड़ी मार्ग को पार करना होता है, जो पगारधारी कर्मचारियों के लिए कभी-कभार अफसर की उपस्थिति में ही संभव है। उल्लेखनीय है कि नायला ग्राम के नवयुवक मंडल के नवयुवकों ने ही दुर्ग को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग को बाध्य किया था। इन लोगों ने ही विभाग को सूचित किया था कि पुरातात्विक अवशेषों के तस्कर दुर्ग से बहुमूल्य वस्तुएं गायब कर रहे हैं और अवैध शराब के निर्माता दुर्ग में शराब बनाने की भाट्ठियां चला रहे हैं।

हाल में जब 'माया' ने विवादास्पद नायला दुर्ग का दौरा किया, तो नक्शा पूरी तरह बदला हुआ पाया। दुर्ग के परंपरागत स्वामी नायला के ठाकुर रामसिंह द्वारा ओबेराय ग्रुप के हाथों बेचे जाने के बाद जैसे इस जगह की किस्मत ही बदल गयी। आज स्थिति यह है कि दुर्ग तक ले जानेवाला पहाड़ी रास्ता दुरुस्त कर दिया गया है और डेढ़ सौ मजदूर दुर्ग को पांच सितारा होटल बनाने में जुटे हैं। 'माया' ने सौदे के बारे में जानकारी हासिल करने का भरसक प्रयास किया, किंतु नायला ठाकुर के न मिलने पर कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी।

इस संबंध में जब नायला के सरपंच से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे मामले की सूचना २४ नवंबर '८८ को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के निदेशक, कलेक्टर जयपुर और इलाके के जमवा रामगढ़ स्थित तहसीलदार को लिखित भेज दी थी। परिणामस्वरूप पुरातत्व विभाग के निदेशक ने अपने जयपुर क्षेत्र के अधीक्षक को जांच के आदेश दिये। दिसंबर '८८ में जांच रिपोर्ट मिल गयी, लेकिन दुर्ग में होटल का निर्माण फरवरी '८९ तक बदस्तूर जारी रहा। मार्च में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि नायला दुर्ग में ओबेराय होटल लिमिटेड ने अवैध कब्जा किया हुआ है।

असमर्थ सरकार : यह तो सिर्फ एक उदाहरण था यह साबित करने के लिए कि राज्य सरकार अपने ऐतिहासिक अवशेषों की रक्षा कर पाने में असमर्थ है और व्यावसायिक समूह इन्हें दुरुस्त करके व्यवसाय के लिए हर कीमत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहत और कानून के इस टकराव में उन लोगों की बन आयी है, जो राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल धन संचय के लिए करते हैं।

उल्लेखनीय है कि होटल व्यवसाय के लिए राज्य सरकार ने १९६५ में राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना की थी। इस निगम के माध्यम से

निश्छल हंसी का नैसर्गिक सौंदर्य

छाया : प्रताप सिंह

बेणेश्वर मेले का विहंगम दृश्य

छाया: प्रताप सिंह

पर्यटन व्यवसाय

खतरा सांस्कृतिक प्रदूषण का

भारत में जितने विदेशी पर्यटक आते हैं, उनमें से एक तिहाई पर्यटक राजस्थान जरूर जाते हैं, लेकिन सरकारी निगम उन्हें वे सुविधाएं क्यों नहीं दे पाते जो उन्हें निजी क्षेत्र के होटलों में मिलती हैं? सरकार पुरातत्व महत्व के स्थानों को निजी क्षेत्र के होटलों में क्यों तब्दील होने दे रही है?

यह निर्विवाद सत्य है कि राजस्थान अपनी वास्तुकला, संगीत एवं रंग बिरंगे मेलों त्यौहारों तथा लोक कलाओं के लिए पूरे विश्व में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इसी आकर्षण ने राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय में सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी आकर्षित किया है। सरकारी क्षेत्र में यह व्यवसाय एक अप्रैल, १९७९ से राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान होटल निगम चलाता है, तथा निजी क्षेत्र में ताज ग्रुप, क्लार्क ग्रुप और वेलकम ग्रुप अपने होटल चला रहे हैं। इन होटल समूहों में ताज ग्रूप के पांच सितारा होटल पांच हैं, जबकि क्लार्क और वेलकम के एक-एक होटल चल रहे हैं। ताज ग्रुप के पांच होटलों में से तीन जयपुर में स्थित हैं, एक उदयपुर में और एक सवाई माधोपुर में है। क्लार्क ग्रुप का होटल जयपुर में प्रतियोगिता में है, जबकि वेलकम ग्रुप के प्रबंध में चलनेवाला जयपुर का मानसिंह होटल उनसे वास्तविक मालिकों ने वापस ले लिया है। अब वेलकम ग्रुप जोधपुर के उमैद पैलेस के प्रबंध तक सीमित है।

व्यवसायीकरण: राजस्थान का पर्यटन व्यवसाय जिस तेजी से अधिकाधिक लाभ कमाने का धंधा बन रहा है, उसी गति से इन होटल समूहों में प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। इस प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप महलों, किलों और हवेलियों के मालिकों की बन तो आयी है, किंतु इस तरह के व्यवसायीकरण से राजस्थान की लोक संस्कृति एवं संरक्षित अवशेषों को जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे लगता है सरकार अभी बेखबर है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में देशी और विदेशी पर्यटकों की आमद में प्रति वर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। मसलन १९७१ में आठ लाख अस्सी हजार देशी पर्यटक राजस्थान आये थे तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या ४२ हजार थी। यही संख्या १९८८ में बढ़कर क्रमशः ३४ लाख ९५ हजार व ३ लाख ६६ हजार हो गयी। पर्यटन के लिए आनेवाले देशी-विदेशी संपन्न पर्यटक पांच सितारा होटलों की सुविधा के इच्छुक होते हैं, उनका मानना है कि महलों और किलों का जो राजसी सुख होता है, उसे राजस्थान सरकार का पर्यटन विकास निगम उपलब्ध करा पाने में असफल रहा है।

पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के होटलों ने पर्यटक की इसी भावना को भुनाने का सफल प्रयास किया। हालांकि सभी ग्रूप अपने प्रयास में उतना सफल नहीं हैं, जितनी सफलता ताज ग्रप ने

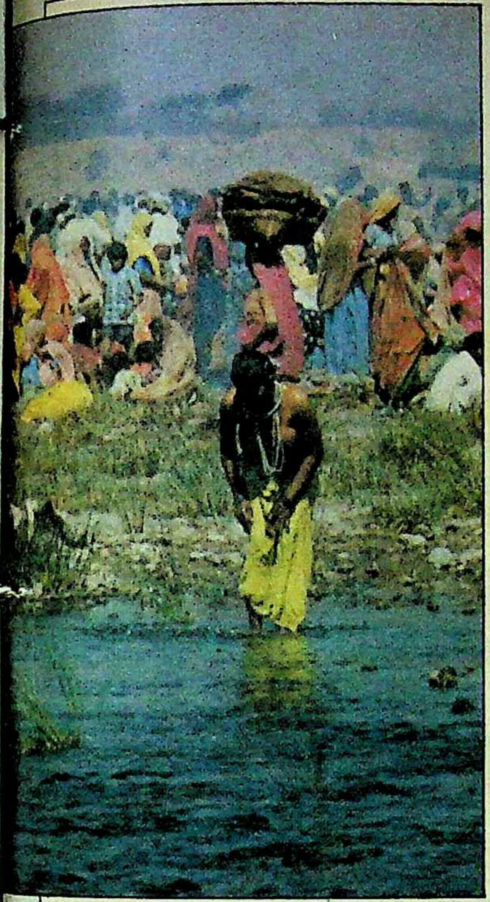

विदेशी कैमरे की नजर यहीं टिकती है

हासिल की है। इस ग्रुप ने जयपुर व उदयपुर के शाही महलों में वही रौनक कर दी है जो राजाओं के जमाने में हुआ करती थी। जयपुर के जयमहल पैलेस में ऐसा मुगल गार्डेन बनाया गया है जिसे यदि शहंशाह अकबर भी देखते, तो चकरा जाते।

दूसरी ओर राजस्थान पर्यटन विकास निगम अपने होटलों में पांच सितारा सुविधा और अपनेपन का वह अहसास देने में पूरी तरह असफल है जिसकी अपेक्षा शाही अवकाश बिताने की इच्छा के साथ राजस्थान आये पर्यटकों को होती है। यही वजह है सरकारी निगम के पीछे रह जाने की।

सांस्कृतिक नुकसान : स्थिति तो यह है कि राजस्थान के पर्यटन आकर्षण को भुनाने के लिए निजी क्षेत्र के वेलकम व ओबेराय ग्रुप ने ऐसे ऐतिहासिक किलों, महलों और हवेलियों को खरीदकर होटलों में बदलने का काम शुरू किया है, जो आज भी विवादास्पद रूप से निजी संपत्ति की श्रेणी में आते हैं। विवादास्पद इन अर्थों में कि राज्य सरकार का पुरातत्व विभाग तो उस संपत्ति को राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान प्राचीन वास्तु अधिनियम, १९६१ की धारा-१७ के तहत संरक्षित घोषित कर चुका है, किंतु परंपरा से उत्तराधिकारी बने लोग इन्हें आज भी अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के २७ जिलों के ऐसे अवशेषों को संरक्षित घोषित करने में तो सरकार के पुरातत्व विभाग ने काफी फुरती दिखायी, लेकिन उन्हें खंडहर बनने से रोक पाने के लिए पुरातत्व विभाग के पास फंड नहीं है।

जयपुर से बीस किलोमीटर दूर ऐसा ही विवादास्पद 'नायला दुर्ग' है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि दुर्ग विशिष्ट निर्माण शैली के इतिहास का अंतिम नमूना है। इस दुर्ग को, भाजपा विधायक नाथूसिंह के अनुसार, नायला ठाकुर रामसिंह ने पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किये जाने के बावजूद ओबेराय ग्रुप के हाथ बेच दिया। जबकि पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों में यह दुर्ग ४ मई, १९८३ को संरक्षित घोषित हुआ है। ऐसे में दुर्ग की खरीद-फरोख्त आश्चर्य का विषय तो है ही।

दरअसल पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक अवशेषों को संरक्षित घोषित तो करता है, किंतु उनका रख-रखाव नहीं कर पाता। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब इस मसले पर चर्चा हुई, तो भाजपा विधायक नाथूसिंह का यही आरोप था। उनके अनुसार इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए एक किलोमीटर लंबे पहाड़ी मार्ग को पार करना होता है, जो पगारधारी कर्मचारियों के लिए कभी-कभार अफसर की उपस्थिति में ही संभव है। उल्लेखनीय है कि नायला ग्राम के नवयुवक मंडल के नवयुवकों ने ही दुर्ग को संरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग को बाध्य किया था। इन लोगों ने ही विभाग को सूचित किया था कि पुरातात्विक अवशेषों के तस्कर दुर्ग से बहुमूल्य वस्तुएं गायब कर रहे हैं और अवैध शराब के निर्माता दुर्ग में शराब बनाने की भाट्ठियां चला रहे हैं।

हाल में जब 'माया' ने विवादास्पद नायला दुर्ग का दौरा किया, तो नक्शा पूरी तरह बदला हुआ पाया। दुर्ग के परंपरागत स्वामी नायला के ठाकुर रामसिंह द्वारा ओबेराय ग्रुप के हाथों बेचे जाने के बाद जैसे इस जगह की किस्मत ही बदल गयी। आज स्थिति यह है कि दुर्ग तक ले जानेवाला पहाड़ी रास्ता दुरुस्त कर दिया गया है और डेढ़ सौ मजदूर दुर्ग को पांच सितारा होटल बनाने में जुटे हैं। 'माया' ने सौदे के बारे में जानकारी हासिल करने का भरसक प्रयास किया, किंतु नायला ठाकुर के न मिलने पर कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी।

इस संबंध में जब नायला के सरपंच से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे मामले की सूचना २४ नवंबर '८८ को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के निदेशक, कलेक्टर जयपुर और इलाके के जमवा रामगढ़ स्थित तहसीलदार को लिखित भेज दी थी। परिणामस्वरूप पुरातत्व विभाग के निदेशक ने अपने जयपुर क्षेत्र के अधीक्षक को जांच के आदेश दिये। दिसंबर '८८ में जांच रिपोर्ट मिल गयी, लेकिन दुर्ग में होटल का निर्माण फरवरी '८९ तक बदस्तूर जारी रहा। मार्च में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि नायला दुर्ग में ओबेराय होटल लिमिटेड ने अवैध कब्जा किया हुआ है।

असमर्थ सरकार : यह तो सिर्फ एक उदाहरण था यह साबित करने के लिए कि राज्य सरकार अपने ऐतिहासिक अवशेषों की रक्षा कर पाने में असमर्थ है और व्यावसायिक समूह इन्हें दुरुस्त करके व्यवसाय के लिए हर कीमत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं।

निश्छल हंसी का नैसर्गिक सौंदर्य

छाया : प्रताप सिंह

चाहत और कानून के इस टकराव में उन लोगों की बन आयी है, जो राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल धन संचय के लिए करते हैं।

उल्लेखनीय है कि होटल व्यवसाय के लिए राज्य सरकार ने १९६५ में राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना की थी। इस निगम के माध्यम से

आओ मिलकर हम 'घर-घर' खेलें !

Practical guide to
home landscaping
IKEA 1987

जब जीवन भर की पूंजी लगायेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिये अपनी निशानी भी तो छोड़ कर जायेंगे।

जी हां! आखिर जीवन भर की पूंजी लगाकर जब अपना घर बनायेंगे तो किसी भी चीज़ में समझौते का सवाल ही नहीं उठता। खासकर सीमेन्ट का चुनाव तो बहुत ही सोच समझकर कीजियेगा।

फिर सबसे बेहतर सीमेन्ट की सही पहचान तो किसी अच्छे बिल्डर को ही हो सकती है, है ना? तो भारत के नं. 1 बिल्डर जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ के वर्षों के अनुभव का फायदा अब आप भी उठाइये। जिस सीमेन्ट से वे बड़े-बड़े पुल और बांध देश-विदेश में बनाते हैं, उसी भरोसेमन्द सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट से आप भी अपना घर बनवाइये।

सीमेन्ट की क्वालिटी का मापदण्ड हमेशा उसमें उपयोग किये गये चूना-पत्थर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इसीलिये सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट का कारखाना देश के सबसे बेहतरीन चूना-पत्थर की खदानों में पास स्थित है। साथ ही साथ सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट अत्याधुनिक कम्प्यूटर युक्त तकनीक से बनाया जाता है।

तभी तो सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट में है बेजोड़ पकड़, लाजवाब मजबूती और बेमिसाल भरोसा।

जब भारत के नं. 1 बिल्डर के अनुभवों से बना सीमेन्ट उपलब्ध है, तो फिर भला किसी और सीमेन्ट को क्यों खरीदें?

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट : इसे नाम से मांगिये।

सुपरप्लस जेपी सीमेन्ट की गारंटी
- तुरन्त मज़बूत पकड़
- 28 दिनों के बदले सिर्फ 3 दिनों में 330 kg/cm^2 की कम्प्रेसिव मज़बूती।
- हर बोरी में पूरा वज़न – पूरे 50 किलो।

GUARANTEED ★ QUALITY ★ Jaypee CEMENT

मज़बूत रहे यह बंधन-जीवनभर

सुपरप्लस
जेपी
सीमेन्ट

मास्टर बिल्डर
जयप्रकाश इन्डस्ट्रीज़ का एक उत्कृष्ट उत्पादन

LINTAS (DELHI) JI 58 2621 Hi

साक्षात्कार : कुमारी गिरिजा व्यास,
पर्यटन राज्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान में पर्यटक शुद्ध संस्कृति का अहसास करने आता है

माया : निगम द्वारा आयोजित मेलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी होती है?

गिरिजा व्यास : शुरू में ऐसा लगा था कि उनकी भागीदारी नहीं होती, पर जब से मैं मंत्री बनी हूं, स्थितियां बदल गयी हैं। मैंने उत्सवों के आयोजन केवल पर्यटकों तक सीमित नहीं रखे। इसी का नतीजा है कि इस वर्ष कोटा संभाग में होनेवाला हाड़ौती-उत्सव स्थानीय लोगों के साथ अपने पूरे लोक रंग में प्रस्तुत हुआ। जैसलमेर के 'मरु-उत्सव' में भी मैंने स्थानीय लोगों को शामिल किया। मैंने अपने विभाग को प्रबंध तथा वित्तव्यवस्था तक सीमित रखने का प्रयास किया है।

माया : लोक उत्सवों को पर्यटन व्यवसाय का आधार बनाने से कहीं लोक-संस्कृति दूषित तो नहीं हो रही?

व्यास : निश्चित रूप से पुष्कर और वेणेश्वर मेले को लेकर हम चिंतित हुए हैं। दक्षिणी-पूर्वी देशों में जिस तरह का पर्यटन होता है, उससे विदेशी पर्यटक प्रभावित हुए हैं। पर वैसी छूट हम राजस्थान में पर्यटन के विकास के नाम पर किसी को नहीं देंगे। पहले इस खतरे ने मुझे भी चौंकाया था, पर अब इन बुराइयों से निबटने के लिए हम नियम-कायदे सख्ती से लागू कर रहे हैं। पुष्कर में नशाखोरी तथा वेणेश्वर में फोटोग्राफी पर पाबंदी लगा दी गयी है।

माया : पर पुष्कर और वेणेश्वर के मेलों की ओर आकर्षित करने की आपकी प्रचार सामग्री तो कुछ और ही कहती है?

व्यास : मैंने अपने मंत्री बनने के बाद ऐसी प्रचार सामग्री को रद्द कर दिया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न पर्यटन एजेंसियों का अनुभव है कि राजस्थान में पर्यटक यहां की शुद्ध संस्कृति का अहसास करने आता है। उसे लुभाने के लिए दक्षिणी-पूर्वी देशों जैसी प्रचार सामग्री का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। यह बात मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को ठीक से समझा दी है। अब हम पुष्कर और वेणेश्वर की चर्चा करते हैं, तो उनके धार्मिक व आध्यात्मिक पक्ष को पर्यटकों के सामने रखते हैं। हमारे प्रचार की भाषा में जब पवित्रता का अहसास होगा, तो पर्यटकों का व्यवहार भी स्वतः ही बदल जायेगा।

माया : आपका विभाग पांच सितारा होटलों जैसा आराम देने में क्यों असफल रहा है?

व्यास : मैं समझती हूं कि राजस्थान में पर्यटक पांच सितारा होटलों का आनंद लेने नहीं आता। किंतु इस बात को भी मानती हूं कि विदेशी पर्यटक ऐसी (पांच सितारा होटलों की) ही व्यवस्था की अपेक्षा करता है। हमने प्रारंभ में चेष्टा भी की, किंतु प्रयास असफल रहा। फिर भी तीन सितारा होटलों जैसी सुविधा तो हम प्रदान करते ही हैं। साथ ही, निजी क्षेत्र में कार्यरत ताज ग्रुप जैसे अन्य समूह ओबेराय, वेलकम, हयात आदि को भी हमने राजस्थान में आमंत्रित किया है। हमारा उद्देश्य पर्यटक को बेहतर सेवा उपलब्ध करवाना है और वह इन समूहों की होड़ से ही संभव हो पायेगा। दरअसल देश में प्रवेश करनेवाले विदेशी पर्यटकों का तिहाई हिस्सा, राजस्थान निश्चित रूप से आता है। बस इन्हें कमी खलती है, तो केवल एअर लिंक और बेहतर सुविधाओं की। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दिक्कतें भी जल्द ही दूर हो जायें।

माया : महलों, किलों और हवेलियों में होटल व्यवसाय आपका विभाग क्यों नहीं करता?

व्यास : हमने इस ओर विशेष प्रयास नहीं किये, लेकिन मैं मानती हूं कि पर्यटकों के रुझान के अनुसार इनका उपयोग होना चाहिए। इस प्रयास में उन ऐतिहासिक अवशेषों को नहीं छेड़ा जाना चाहिए जिनका पुरातात्विक महत्व है।

माया : पुरातत्व विभाग क्या ऐसी संपत्ति की देखभाल कर पाता है?

व्यास : संभवतः कर पाता है। जिनकी नहीं कर पाता, उन्हें खंडहरों में बदल जाने से पूर्व व्यवसाय में इस्तेमाल करता है। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

माया : नायला फोर्ट के होटल में तब्दील होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

व्यास : देखिये अगर पुरातत्व विभाग का संबंध नहीं है और किसी की निजी संपत्ति है, तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हम ऐसे व्यवसाय को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं, जो हमारे पर्यावरण को सुधारने यानी मितरी लाने में भी मदद करें। होटल व्यवसाय के लिए यह शर्त जरूरी है। हमारा अनुभव है कि इस मामले में निजी क्षेत्र काफी ईमानदार है।

माया : पर्यटन को उद्योग घोषित करने के पीछे आपका क्या मंशा है?

व्यास : व्यवसायियों और कर्मचारियों को उद्योग वाले काम मिलें। यानी वित्त, भू-खंड इत्यादि में प्राथमिकता मिलेगी और व्यवसाय विकसित होगा। इसी परिकल्पना के तहत इसे उद्योग घोषित किया गया है। —ओम सैनी

जयपुर की खासा कोठी होटल और उदयपुर का होटल आनंद भवन तथा उदयपुर व जयपुर के हवाई अड्डों पर केफेटेरिया भर चलते हैं। राज्य के डेढ़ दर्जन निगमों में से केवल छह लगभग मुनाफे में चल रहे हैं। मुनाफेवाले निगमों की गिनती में प्रदेश का राज्य होटल निगम भी आता है। इसी होटल निगम की खासा कोठी होटल का सौदा पूर्व जोशी सरकार ने मई '८७ में लगभग तय कर दिया था। हुआ यह कि मई '८७ में राज्य सरकार के पर्यटन, संस्कृति एवं कला विभाग की ओर से स्थानीय अखबारों में विज्ञापन छपवाया गया कि राज्य सरकार जयपुर शहर के मध्य में स्थित अपनी बहुमूल्य संपत्ति पर चार, पांच सितारा होटल बनाने के लिए इच्छुक पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। विज्ञापन में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह संपत्ति कौन सी है? क्योंकि जयपुर शहर में तो राज्य सरकार के ऐसे तीन भवन हैं—खासा कोठी, गवर्नमेंट होस्टल और हिंद होटल। विज्ञापन की इस अस्पष्ट भाषा को स्पष्ट किया राजस्थान राज्य होटल निगम कर्मचारी संघ ने। इन लोगों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खासा कोठी होटल को वेलकम ग्रुप को सौंपने की तैयारी कर रही है। क्योंकि होटल कर्मचारियों ने देखा कि वेलकम ग्रुप के प्रबंधक एक माह से खासा कोठी होटल में रुके हुए हैं और उन्हें अपने कमरे में निजी फोन लगाने की अनुमति भी राज्य सरकार ने दे दी है।

रहस्यमय विज्ञापन : २८ मई '८७ को राज्य सरकार अपने कथित विज्ञापन के बाद, टेंडर वेलकम ग्रुप के नाम खोलने ही वाली थी कि तभी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रसेन इसरानी ने राजस्थान राज्य होटल निगम कर्मचारी यूनियन तथा जयपुर के ठाकुर हनुमंत सिंह आलूदा द्वारा तत्काल दायर की गयी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद २७ मई को राज्य सरकार को, खासा कोठी को निजी क्षेत्र में देने के लिए मई तक आमंत्रित निविदा विज्ञप्ति पर, कोई कार्यवाही न करने के निर्देश दिये। कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर याचिका में स्पष्ट कहा गया था कि खासा कोठी होटल को बेचने या लीज पर देने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खासा कोठी राज्य होटल निगम की इकाई है, न कि राज्य सरकार की। ऐसे में इसके बारे में निगम ही कोई निर्णय कर सकता है। चूंकि निगम ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए खासा कोठी की प्रस्तावित बिक्री या उसे दीर्घकालीन पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही अवैध है। फिर यदि निगम खुद भी इसे बेचना चाहे, तो उसे हिस्सेदारों की सामान्य बैठक में निर्णय लेना पड़ेगा।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि कंपनी कानून की धारा १७ के तहत खासा कोठी को बेचने या पट्टे पर देने की कार्यवाही निगम तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि इस कार्यवाही से प्रभावित होनेवाले कर्मचारियों को नोटिस नहीं दिया जाये। इस नोटिस के लिए निगम को कंपनी ला बोर्ड से इजाजत लेनी होगी।

**गतिशील
राजस्थान**

नारी जागरण का अलख

राजस्थान में विगत वर्ष नारी चेतना और कल्याण के लिए समर्पित बर्ष रहा है। लोक-शिक्षण के विभिन्न माध्यमों से जहाँ नारी सम्बन्धी प्रतिगामी मानसिकता को तोड़ने का प्रभावी उपक्रम किया गया है, वहाँ नारी-कल्याण के लिए अनेक कारगर उपाय किये गये हैं। शासन के ये निर्णय इसी पुनीत लक्ष्य के परिचायक हैं :—

- प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक की नारी-शिक्षा नि:शुल्क
- विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा का प्रतिबन्ध समाप्त
- रोजगार कार्यालयों के जरिए नियुक्ति पाने की बाध्यता समाप्त
- सीधी भर्ती के पदों पर विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति
- राज्य सेवा में नियुक्ति पर लागू प्रतिबन्ध विधवाओं और महिलाओं के लिए नहीं
    - पोलीटेक्नीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थान आरक्षित : ५० प्रतिशत स्थानों पर प्राथमिकता से प्रवेश की सुविधा
    - अधिकतम आयु सीमा में १० वर्ष की छूट—शिक्षण शुल्क से भी मुक्त बीकानेर व अजमेर में दो महिला पोलीटेक्नीक
    - बाडमेर—जालौर में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को वजीफे की व्यवस्था प्रतिमाह
- महिला उद्यमी व दस्तकारों की विशेष सुविधाएं देने के लिए वित्त निगम में समन्वय कक्ष की स्थापना
- अत्याचारों की रोकथाम के लिए विशेष पुलिस प्रकोष्ठ का संचालन

**सूचना
एवं
जन सम्पर्क
निदेशालय,
राजस्थान
द्वारा प्रसारित**

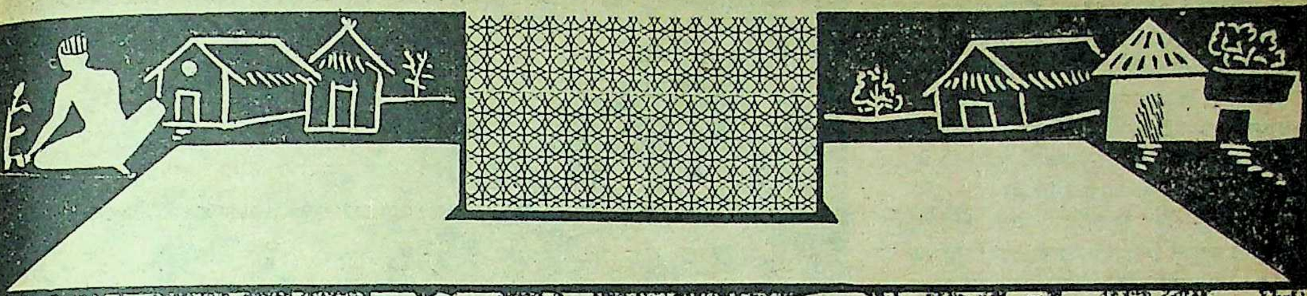

गतिशील राजस्थान
ग्रामवासियों से सीधा संवाद

वर्ष 1988 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करा कर वर्तमान शासन ने लोकतान्त्रिक मूल्यों और पंचायती राज व्यवस्था में अपनी आस्था और प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

● आज सुदूर देहातों के 80 हजार जन प्रतिनिधि राज्य के विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं।

● पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाया गया है।

● समस्त प्राथमिक शालाओं ब उच्च प्राथमिक शालाओं का संचालन आयुर्वेदिक औषधालयों का संचालन और हैण्डपम्पों का रख-रखाव जिला परिषदों को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

प्रतिदिन अधिकाधिक सक्षम बन रही पंचायती राज संस्थाएं अब गांवों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के प्राणवान घटक बनती जा रही हैं। इनके माध्यम से ग्राम-राज की कल्पना मूर्त रूप ले रही हैं।

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा प्रसारित

यूनियन की ओर से यह भी कहा गया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २५ ओ के तहत किसी भी इकाई को कुछ निश्चित कारणों से ही बंद किया जा सकता है। चूंकि खासा कोठी होटल मुनाफे में चल रहा है, इसलिये इसे बंद करना उचित नहीं होगा। खासा कोठी होटल से सन '८७ में दस लाख के लगभग का लाभ हुआ था।

जयपुर के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हनुमंत सिंह आलूदा ने अपनी याचिका में कहा था कि खासा कोठी सवा सौ वर्ष पूर्व जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई रामसिंह ने बनवायी थी। चालीस हजार वर्ग फुट के खुले वातावरण में बने इस भवन को बेचने व नये निर्माण से क्षेत्र के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बेचने की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि निविदा आमंत्रित करने के बाद की सात दिन की अवधि ही निर्णय के लिए अंतिम तिथि रखी गयी है। आगे कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की फर्मों से निविदाएं मांगी गयी हैं, मगर विज्ञापन केवल जयपुर के दो स्थानीय अखबारों में दिया गया।

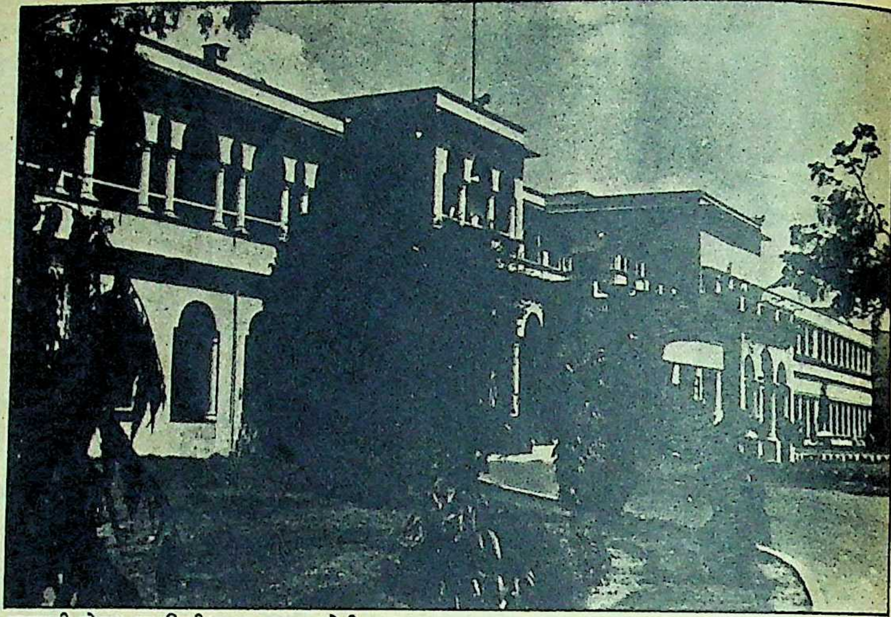

सरकारी होटल का निजीकरण: खासा कोठी

छाया: गोपाल संगर

मुख्यमंत्री की दिलचस्पी: इस याचिका ने उस रहस्य का खुलासा किया कि आईटीसी या वेलकम ग्रुप के हाथ खासा कोठी क्यों बेची जा रही है? याचिका में दर्ज किया गया था कि जयपुर के पांच सितारा होटल मानसिंह के मालिकों से आईटीसी के समझौते की अवधि समाप्त होने से उन्हें दूसरे होटल की जरूरत है। आईटीसी के प्रबंधकों की इस जरूरत को पूरा करने के लिए विज्ञापन जानबूझ कर स्थानीय अखबारों तक सीमित रखे गये।

बहरहाल, अंत में याचिका का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी पर जनता दल के विधायक माणकचंद सुराणा ने आरोप लगाया था कि तीस करोड़ रुपए मूल्य की खासा कोठी को निजी या दिखावे के तौर पर संयुक्त क्षेत्र में दिये जाने के पीछे मुख्यमंत्री की विशेष दिलचस्पी थी।

खासा कोठी होटल निजी क्षेत्र को सौंपने के पीछे मुख्यमंत्री की क्या दिलचस्पी थी यह बताना तो कठिन है, किंतु यह कहना गलत न होगा कि यदि राजस्थान का पुरातत्व विभाग अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह नहीं करता और राजस्थान की पर्यटन विकास निगम अपनी दयनीय स्थिति में सुधार नहीं लाता, तो एक-एक करके ऐतिहासिक महत्व की इमारतें यों ही पर्यटन व्यवसाय की भेंट चढ़ती रहेंगी। पर्यटन के व्यवसायीकरण के क्या दुष्परिणाम होंगे यह राज्य सरकार भलीभांति जानती है। उसे कोई ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे क्योंकि यदि पर्यटकों को आकर्षित करने वाली वास्तुकला ही न बचेगी, तो पर्यटन व्यवसाय से लाभ कैसे होगा?

—ओम सैनी

प्रदूषण का जहर घोलते उत्सव

राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रदेश के पर्यटन स्थलों को सात क्षेत्रों, मेवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, जयपुर-अलवर-भरतपुर, जयपुर-टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर-जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर तथा माउंट आबू में विभाजित कर रखा है। इन क्षेत्रों में अलग-अलग जगह वर्ष भर में तेरह उत्सव आयोजित किये जाते हैं।

ये उत्सव ही राजस्थान की अछूती लोक संस्कृति में प्रदूषण का जहर घोल रहे हैं, जिसकी शिकायत तीर्थराज पुष्कर में 'पुष्कर बचाओ समिति' के नेता करते हैं, तो वेणेश्वर में आदिवासी नवयुवक। कहा जाता है कि तीर्थराज पुष्कर पौराणिक तपोभूमि और लोक संस्कृति का चेतना केंद्र रहा है। यही वजह थी कि जब मध्यकाल में राजपूताने की छोटी-बड़ी रियासतें बैर और प्रतिस्पर्धा की आग में जल रही थीं, तो पुष्कर ही एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक केंद्र था, जहां आकर समग्र देश का खंडित विभाजित लोक मानस अनेकता से एकता के सूत्र में बंधता था।

लोकमानस के इसी केंद्र बिंदु को राजस्थान राज्य पर्यटक निगम के पर्यटक उत्सव ने दूषित किया है। सरकार का पशुपालन विभाग इसे केवल पशु मेले के रूप में प्रचारित करता है, तो पर्यटन विभाग 'पर्यटक मेले' का नाम देकर इसके सांस्कृतिक महत्व को समाप्त कर रहा है। पर्यटक मेले की प्रचार सामग्री में दर्ज किया जाता है 'मदभरी ताल पर थिरकते पांव, अल्हड़ सुंदरियों के झुंड, घाघरों के घेरे,' जबकि पुष्कर वास्तव में रंगों, उमंगों और उल्हासित तरंगों का मेला है। देश-विदेश के पर्यटक भी मेले में यही तलाश करते हैं।

यही हाल डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर मेले में होता है। इस मेले में आदिवासी माही-सोम और जाखर नदी के संगम में अपने पुरखों की आत्माओं को पिंडदान करते हैं तथा वर्ष भर में दिवंगत हुए आत्मजनों की अस्थियां त्रिवेणी संगम में अर्पित करते हैं। उदयपुर से १६० किलोमीटर दूर बने इस संगम स्थल पर विचित्र किस्म का शिवालय है। इस शिव मंदिर को ही वेणेश्वर कहा जाता है। माघ माह की पूर्णिमा को आदिवासी अपने आत्मजनों की अस्थियों के साथ यहां आते हैं। इन अस्थियों के पात्र को अपनी भाषा में वे 'कुलकी' कहते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन भोर होते ही 'कुलकी' विसर्जित की जाती है। इस अनुष्ठान को आदिवासी परिवार निस्संकोच करते हैं। पूरा परिवार स्नान, ध्यान और भोजन में मगन नजर आता है। इन्हीं दृश्यों को तमाशबीन पर्यटक अपने कैमरे में सुरक्षित करता है। तीन दिन चलनेवाले इस मेले में आदिवासी बालाओं का खुलापन सभ्य समाज की समझ से बाहर होता है।

—ओम सैनी

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

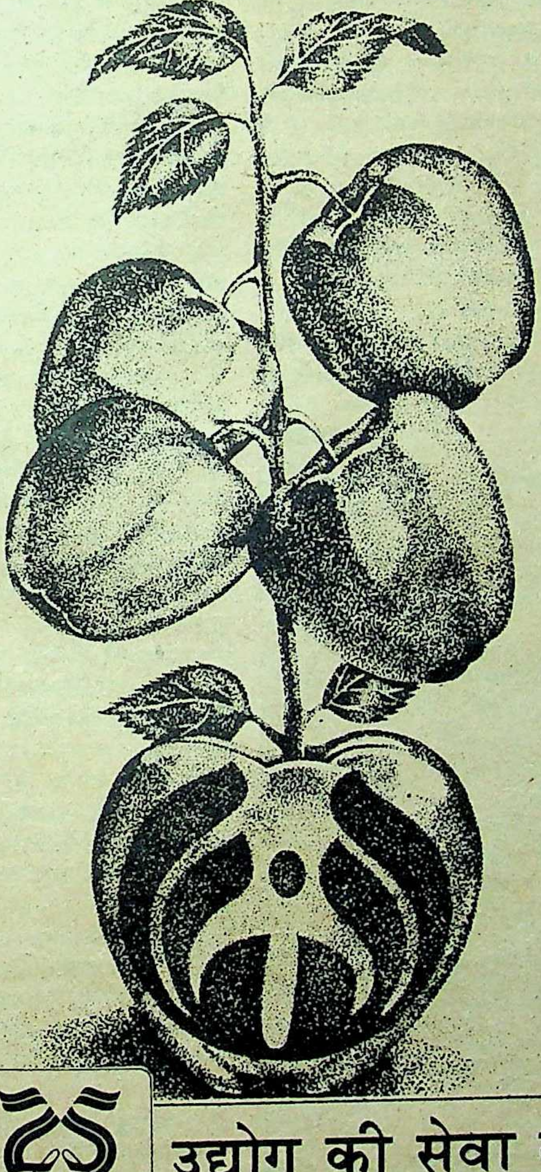

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

1964-1989 SILVER JUBILEE YEAR

उद्योग की सेवा का 25 वाँ वर्ष

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

जॉली मेकर चेंबर्स नं. 2, 225, विनय के. शाह मार्ग, नरिमन पॉइंट, बम्बई 400 021.

Sobhagya-B/89 HN

कांग्रेस की चुनावी मुहिम

विपक्ष गफलत में ?

राजस्थान में कांग्रेस-इ ने तो मध्यावधि चुनाव कराने का मन बनाकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन भाजपा को छोड़कर प्रमुख विपक्षी दल देवीलाल-अजीत सिंह व वीपी सिंह के बनते-बिगड़ते समीकरणों में ही उलझे हुए हैं। क्या राजस्थान में विपक्ष का रहासहा वजूद भी खतरे में पड़ गया है ?

राजस्थान का विपक्ष अभी आपसी झंझटों में ही फंसा हुआ है, जबकि कांग्रेस असंतुष्टों के कोहराम के बावजूद चुनावी तैयारियों में लग गयी है। कांग्रेस-इ आलाकमान के विशेष आदेश के तहत राजस्थान के ३८ हजार गांवों में सात से ग्यारह सदस्योंवाली ऐसी कमेटियां गठित की जा रही हैं, जिनमें मूल दल व उसके अग्रणी संगठनों—महिला, युवक, छात्र-एवं सेवादल के कार्यकर्ता शामिल होंगे। ९ अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत ने इस निर्णय से प्रेस को अवगत कराया और १४ अप्रैल को उन पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी, जिनकी देख-रेख में यह काम होना है। इस सूची में गौरतलब बात यह है कि लगभग सभी असंतुष्टों को प्रदेश की चालीस जिला कमेटियों और ४६४ ब्लाक कांग्रेस-इ कमेटियों के गठन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस ने अपने बंद कमरे की बैठक में यह भी निर्णय लिया है कि ब्लाक स्तर की कमेटियों की यह जिम्मेदारी होगी कि विपक्ष जहां भी अपनी जनसंभा करे, कांग्रेस-इ अपनी विशेष सभा द्वारा उनकी जनसभाओं को प्रभावहीन बनाये। इस रणनीति के संबंध में अशोक गहलोत ने 'माया' को बताया, "हमारी वर्तमान योजना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आमंत्रित प्रदेश कांग्रेसाध्यक्षों व मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री एवं कांग्रेसाध्यक्ष श्री राजीव गांधी द्वारा विचार-विमर्श के बाद तैयार की गयी है।" गहलोत के अनुसार, "हमारे जन-जन तक पहुंचने के अभियान का अर्थ यह है कि हम अपने गांव की इकाई से समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी निभायें।" यद्यपि संगठन को सक्रिय करने की योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही है, लेकिन राजस्थान में जिस तेजी से इस योजना पर काम हो रहा है, उससे लगता है कि आलाकमान प्रदेश कांग्रेस-इ की सरफुटौवल को समाप्त करने और द्वंद्व में फंसे विपक्ष को झटका देने के लिए राजस्थान में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव कराने की सोच रहा है।

ऐसे ही संकेत अप्रैल माह में राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस के जोधपुर में आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन के दौरान भी मिले हैं। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस-इ की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने, गांवों की दीवारों को धर्म निरपेक्षता के नारों से रंगने और पिछड़े वर्गों के दुख-दर्द में भागीदार बनने की बातें बड़े जोर-शोर से कही गयीं। चुनावी संकेत इस बात से भी मिलता है कि इंका हरिजनों व जनजातियों को हर तरह से खुश करने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है। पिछले चार सालों से निलंबित आईपीएस अधिकारी रोहिताश्व कुमार को जांच में निर्दोष पाये जाने के बावजूद बहाल नहीं किया जा रहा था। इस अन्याय के खिलाफ 'माया' ने भी अपने १५ दिसंबर, १९८८ के अंक में आवाज उठायी थी। लेकिन अब अचानक चुनावी लाभ के लिए उन्हें बहाल कर दिया गया है। इस अधिकारी के निलंबन के खिलाफ पिछड़े वर्ग के लगभग सभी विधायकों ने ज्ञापन भी दिये थे।

अंदर कुछ, बाहर कुछ : चाहे अंदर-ही-अंदर कितना ही द्वेष क्यों न हो, लेकिन कांग्रेसी दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि उनको एक दूसरे से कोई गिला-शिकवा नहीं। अशोक गहलोत तो अब यह भी कहने लगे हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर अपने मंत्रिमंडल की बैठकों में सहयोगियों को निर्देश दे रहे हैं कि वे इंका विधायको और सांसदों का पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही लगता है कि असंतुष्टों के भय से मुक्त होने के लिए स्थगित बजट सत्र के सत्रावसान की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरी हुआ, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में पुन: विधानसभा की बैठक आहूत की जायेगी। इस बीच असंतुष्टों को संतुष्ट बनाने का प्रयास किया जायेगा। पर यह होगा तभी, जब मध्यावधि चुनावों की बात गौण कर दी जायेगी।

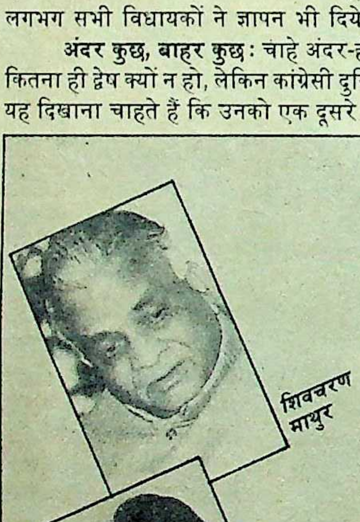
शिवचरण माथुर

अशोक गहलोत

कांग्रेस असंतुष्टों के कोहराम के बावजूद चुनावी तैयारियों में लग गयी है।

फिलवक्त इस बात के संकेत हैं कि आलाकमान ने राजस्थान को मध्यावधि चुनावों के लिए तैयार रहने को कह दिया है। यह अलग बात है कि सारी तैयारी के बावजूद हार का भय आलाकमान को अपना निर्णय बदलने के लिए बाध्य कर सकता है। वैसे सरकार और संगठन में परिवर्तन का शोर जिस तरह से अचानक मद हुआ है, उससे लगता है कि आलाकमान ने राजस्थान में पचायत चुनाव और उप चुनावों के परिणामों को सरकार एवं संगठन की उपलब्धि मान लिया है। फिर भी अगर राजस्थान में सरकार अथवा संगठन-नेतृत्व में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसका एकमात्र कारण विपक्ष के 'जातीय समीकरण' को प्रभावहीन् करना होगा। मसलन, प्रदेश के किसान मतों को प्रभावित करनेवाला जनता दल का जाट-राजपूत गठबंधन कांग्रेस-इ के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। नाथूराम मिर्धा व प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष दौलतराम सारण जहां जाट समुदाय में अपनी पैठ रखते हैं, वहीं प्रदेश विधायक दल के नेता कल्याण सिंह कालवी राजपूतों के एकछत्र नेता होने का दावा करते हैं। कांग्रेस-इ इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है अथवा फिर प्रभावी जाट व राजपूत नेताओं को मंत्रिमंडल में ले सकती है।

उधेड़बुन में विपक्ष : कांग्रेस-इ की इस चुनावी रणनीति के मुकाबले राजस्थान का विपक्ष अभी इसी उधेड़बुन में है कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा ? यह सवाल जनता दल के निर्माण के बाद पैदा हुआ है। यह हास्यास्पद सवाल तब खड़ा किया जा रहा है, जब कांग्रेस-इ राजस्थान में

मध्यावधि चुनावों की तैयारी में लग गयी है। बहरहाल, राजस्थान में जनता पार्टी और लोकदल के विलय के बाद बने जनता दल की सदस्य संख्या विपक्ष के मौजूदा नेता भैरों सिंह शेखावत के दल भाजपा के लगभग बराबर है। पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से अड़तीस विधायक चुनकर आये थे। विपक्षी दलों में यह सबसे बडी संख्या थी, जिसके परिणामस्वरूप इस दल के नेता शेखावत को विपक्ष के नेता का दर्जा हासिल हुआ। बाद में इस दल के एक विधायक मालाराम की मृत्यु हो गयी और संख्या घट कर सैंतीस रह गयी। पार्टी के एक अन्य विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी चुनाव याचिका सबंधी विवाद में फंसे हुए हैं। इस विवाद के कारण वे मत देने और सदन में भाषण देने के अधिकार से वंचित हैं। वे केवल सदन में बैठ कर अपनी हाजिरी दर्ज करवा सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष को अगर गिना जाता है, तो शेखावत को सैंतीस मतों का समर्थन हासिल है अन्यथा उनके साथ कुल ३६ विधायक हैं। दूसरी ओर जनता दल के सदस्यों की संख्या उसके घटक जनता पार्टी और लोकदल के सदस्यों को मिलाकर सैंतीस बनती है। इनमें भी लोकदल के अब्दुल अजीज को राजीव गांधी की कांग्रेस-इ में उज्ज्वल भविष्य नजर आने लगा है। ऐसे में यह संख्या घट कर छत्तीस रह जाती है। विधानसभा में दो विधायक जनमोर्चा के हैं, लेकिन उन्हें जनता दल का सदस्य वैधानिक रूप से नहीं माना गया है। ऐसे में विपक्ष के नेता होने का रुतबा भाजपा के भैरों सिंह शेखावत के पास बरकरार है।

जनता दल के गठन से पूर्व भाजपा के शेखावत, लोकदल के नाथूराम मिर्धा और जनता पार्टी के कल्याण सिंह कालवी को अपने-अपने दलों में युवाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था। संकट की ऐसी स्थिति में तीनों बड़े नेता एकमत थे, तीनों का अपना सोच था कि जातिवाद के समीकरण और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से वे राजस्थान में विपक्ष की सरकार बना सकते हैं। नाथूराम मिर्धा ने जयपुर में प्रभावी किसान रैली आयोजित कर अपना दबदबा दिखाया था, तो कल्याण सिंह कालवी ने 'सती-कांड' के दौरान राजपूतों के नेता होने की बात स्थापित की थी। भाजपा के भैरों सिंह शेखावत को एक प्रकार से कालवी ने राजपूतों के नेतृत्व से पदच्युत कर दिया था। शेखावत का यह घाव हमेशा हरा रहा है, पर जातीय समीकरण के वर्तमान रचयिता नाथूराम मिर्धा दोनों नेताओं के बीच मधुर संबंधों का कारण बने रहे। सिद्धांतविहीन इस एकता में दरार आयी है, जनता दल के गठन के बाद। इस दरार का ही नतीजा है कि जनता विधायक दल के नेता कल्याण सिंह कालवी शेखावत के विपक्ष के नेता होने को चुनौती दे रहे हैं।

प्रदेश जनता दल के नेताओं की प्रतिस्पर्द्धा का भी अपना आलम है। शुरू में जनता दल की पूर्व पीठिका के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जनमोर्चा बना, जिसके प्रदेश में संयोजक नियुक्त हुए निर्दलीय विधायक मोहन छंगाणी। मोहन छंगाणी राजस्थान में जनमोर्चा गठित करते, उससे पहले ही बन गया जनता दल। जनता दल में राजस्थान के संदर्भ मे पहले बोलबाला रहा हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का। भाजपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले देवीलाल ने राजस्थान कें संदर्भ में झटका दिया बहुगुणा समर्थक तत्कालीन प्रदेश लोकदल अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा को। इस झटके के लिए उन्होंने चुना लोकदल के समाजवादी विधायक मोहन प्रकाश को। मोहन प्रकाश जनता दल के गठन का समाजवादी प्रारूप बना ही रहे थे कि अजीत सिंह की मदद से नाथूराम मिर्धा प्रभावी हो गये। खुद राजस्थान में जनता दल के अध्यक्ष बने और जनता पार्टी के विवादास्पद प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह कालवी को विधायक दल का नेता बनवा दिया। परिणामस्वरूप आज वीपी सिंह-समर्थक मोहन छंगाणी जनता दल में प्रभावहीन हैं, तो विपक्ष की सैद्धांतिक एकता के पक्षधर जनता पार्टी के समाजवादी विधायक प्रोफेसर केदार, मानिकचंद सुराणा इत्यादि मिर्धा-कालवी गुट से मात खा चुके हैं, राजस्थान का जनता दल आज देवीलाल-अजीत सिंह और वीपी सिंह के बनते-बिगड़ते समीकरणों के दलदल में फंसा है। देवीलाल चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संसदीय बोर्ड अध्यक्ष तथा मुख्य महासचिव के महत्वपूर्ण पदों पर उनके किसी अनुयायी की नियुक्ति हो, पर हुआ इसके विपरीत। इन विपरीत परिणामों के बाद देवीलाल गुट ने शक्ति-परीक्षण किया जनता दल विधायक दल के नेता के निर्वाचन के दौरान। १२ अप्रैल को जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में विधायक दल के नेता के निर्वाचन की औपचारिक बैठक के पूर्व मिर्धा गुट के छब्बीस विधायकों ने मिर्धा के निवास पर ही कल्याण सिंह कालवी को विधायक दल का नेता बनाने का निर्णय कर लिया था। जब बैठक शुरू हुई, तो देवीलाल गुट की ओर से जनता पार्टी घटक के विधायक प्रोफेसर केदारनाथ का नाम नेता के लिए पेश हुआ, तो मिर्धा गुट की ओर से पूर्व निश्चय के अनुसार कल्याण सिंह कालवी का नाम लिया गया। बड़े नेताओं ने सर्वसम्मत चुनाव के लिए बहुत से रास्ते निकाले, लेकिन बात नहीं बनी। अनिर्णय की इस स्थिति में देवीलाल गुट के विधायक मोहन प्रकाश और मानिकचंद सुराणा ने गुप्त मतदान का सुझाव दिया। जद के राष्ट्रीय महासचिव यशवंत सिन्हा ने बीच का रास्ता निकाला और एक-एक विधायक से नेता के नाम पर जबानी राय ले ली। निर्णय मिर्धा गुट के पक्ष में जाना ही था और इस तरह कल्याण सिंह कालवी जनता विधायक दल के नेता चुन लिये गये।

भैरों सिंह शेखावत
नाथूराम मिर्धा
कल्याण सिंह कालवी
दौलतराम सारण

विपक्ष में भाजपा ऐसा एकमात्र दल है, जो संगठन के स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटा है।

इस चयन के बाद से जद के जनता पार्टी घटक के समाजवादी विधायक काफी खिन्न हैं। 'माया' ने इन लोगों से टिप्पणी करने को कहा, तो वे बोले कि 'वे जातिवाद के कभी समर्थक नहीं रहे, पर अब जातिवाद की छवि वाले जनता दल के सदस्य होने का दंड भोग रहे हैं।' विपक्ष की एकता का आलम यह है कि विपक्षी दल विधानसभा में विपक्षी नेता-पद के लिए जहां एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, वहीं पिछले उपचुनावों में भाजपा से तालमेल न बिठाने के कारण हार के बावजूद भाजपा से हाथ मिलाने की कोई सूरत नहीं निकाल पा रहे। प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा ने विपक्ष की इस दरार को मकराना में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराकर और चौड़ा किया है। मिर्धा का यह बयान भाजपा के अंदरूनी कलह में जहां विपक्ष के नेता भैरों सिंह शेखावत के पक्ष में नजर आता है, वहीं आरएसएस प्रधान भाजपा संगठन को नकारने वाला लगता है। भाजपा के प्रदेश मंत्री दामोदर शर्मा ने इस बयान को विपक्ष को विभाजित करने की साजिश बताया है। इन विवादों के रहते कांग्रेस-इ अगर मध्यावधि चुनावों के माध्यम से विपक्ष को चुनौती देती है, तो राजस्थान में वह बिना किसी लहर के पुनः सत्ता में आ सकती है। फिलवक्त विपक्ष में भाजपा ऐसा एकमात्र दल है, जो संगठन के स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटा है, अन्यथा जनता दल तो राजस्थान के संदर्भ में ऐसे नारे भी तलाश नहीं कर पाया है कि जिन्हें देख कर यह कहा जा सके कि वह कांग्रेस-इ की किसी चुनौती का मुकाबला भी कर सकता है।

—ओम सैनी

आखिर क्यों बंद हुई सरकारी लाटरी ?

बड़े धूमधड़ाके के साथ १९६९ में शुरू हुई मध्यप्रदेश की सरकारी लाटरी ने १९८६ में चुपचाप दम क्यों तोड़ दिया ? क्या वह निजी लाटरियों का मुकाबला नहीं कर पायी या खुद सरकारी अफसरों ने ही अपने निहितस्वार्थों के कारण उसकी मौत का सारा इंतजाम कर दिया था ? चुरहट लाटरी-प्रसंग से इस संबंध में कौन से नये तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

तीन साल पहले मप्र शासन की सरकारी लाटरी ने निजी लाटरियों के मुकाबले की तेज दौड़ में दम तोड़ दिया था। मप्र सरकार ने पहलेपहल लाटरी सन १९६९ में निकाली थी, जो ७०-८० के दशक में प्रतिस्पर्धा में जीवित रही। अगले दशक में भी उसकी अकाल मौत नहीं होती, यदि निजी लाटरियों से उसकी स्वस्थ होड़ होती और आला-अफसर उसकी ओर समुचित ध्यान देते। सरकारी लाटरियों के ठप हो जाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है ? इस सवाल के जवाब के लिए लाटरियों से जुड़े तमाम संदर्भों को खंगालना जरूरी है। तत्कालीन वित्तसचिव और संचालक अल्पबचत और लाटरी के मध्य पत्राचार और कतिपय टिप्पणियां इस प्रश्न के उत्तर की खोज की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान सामग्री हैं। मार्च, १९८४ में इंदौर टेबिल टेनिस ट्रस्ट को लाटरी की अनुमति मिलने का प्रकरण शासन के विचाराधीन था। तत्कालीन उपसचिव वित्त अस्थाना ने २८ मार्च को अपनी टीप में फ्लाईंग क्लब और इंडियन रेडक्रास को रैफल की अनुमति का हवाला देते हुए लिखा कि इस तरह तो हमें अपनी लाटरी बंद करनी पड़ेगी।

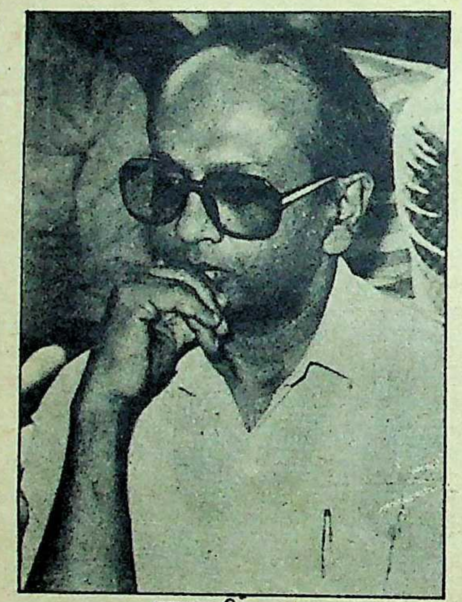

एमआर शिवरमन

उपसचिव की यह साफगोई और चेतावनी लगता है कि तत्कालीन वित्तसचिव एमआर शिवरमन को पसंद नहीं आयी। शिवरमन ने उपसचिव की टीप के नीचे अनुमति देने की पैरवी करते हुए लिखा कि लाटरी पर असर पड़ने की उपसचिव की बात सही नहीं है। उपसचिव को विवरण ज्ञात नहीं है, क्योंकि वह सेक्शन के अस्थायी प्रभार में हैं। वित्तसचिव की यह टिप्पणी रंग लायी और इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट को ड्रा की अनुमति मिल गयी।

वित्तसचिव की भूमिका: चाहे निजी लाटरियों को अनुमति मिलने का मामला हो या सरकारी लाटरी के अप्रत्याशित हस्र का, संदेह की सुई शिवरमन की ओर सरकती नजर आती है। चुरहट लाटरी के मामले में सीधी के कलेक्टर की काफी लानत-मलामत हुई है। सचाई यह है कि शिवरमन ने कलेक्टर को लिखित हिदायत दी थी कि वह सोसायटी को ड्रा की अनुमति दे दें, क्योंकि शासन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वित्तसचिव ने १६ दिसंबर, १९८३ को जिलाधीश को एक पत्र लिखा कि आप चिल्ड्रेन वेल्फेयर' सोसायटी को लाटरी अधिनियम की धारा-७ के तहत रैफल निकालने के लिए, जब वह आवेदन करें, लाइसेंस देने की कृपा करें। वित्तसचिव ने इसी आशय का एक तार अगले दिन कलेक्टर को भेजा, जबकि संस्था के सचिव अजय सिह ने लाइसेंस के लिए अर्जी करीब एक पखवाड़े बाद २९ दिसंबर, १९८३ को दी।

> **सचाई यह है कि शिवरमन ने कलेक्टर को लिखित हिदायत दी थी कि वह सोसायटी को ड्रा की अनुमति दे दें, क्योंकि शासन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वित्तसचिव ने १६ दिसंबर, १९८३ को जिलाधीश को एक पत्र लिखा कि आप चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी को लाटरी अधिनियम की धारा-७ के तहत रैफल निकालने के लिए, जब वह आवेदन करे, लाइसेंस देने की कृपा करें।**

राज्य शासन की साप्ताहिक लाटरियों को लें, तो शिवरमन का रवैया पल्ले नहीं पड़ता। लाटरी एवं अल्प बचत संचालनालय के तत्कालीन संचालक स्वरूप सिह पोर्ते ने इंदौर की वैभवशाली लाटरी को अनुमति देने और मैसर्स चंद्रा एजेंसीज के उनका सोल एजेंट नियुक्त होने पर कड़ी आपत्ति की थी। पोर्ते की आशंका थी कि चंद्रा एजेंसी सरकारी लाटरी के मुकाबले अधिक मूल्य और अधिक पुरस्कार वाली वैभवशाली लाटरी में रुचि लेगी, लिहाजा सरकारी लाटरी पर विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने अपने पत्रों से व मुलाकातों के जरिये वित्तसचिव का ध्यान इस ओर लगातार आकृष्ट किया, किंतु वित्तसचिव के कानों पर जूं नही रेंगी। पोर्ते की आशंका कालांतर में खरी उतरी और सरकारी लाटरी को अंततोगत्वा बंद कर देना पड़ा।

केंद्र की तौहीनी: सरकारी व निजी लाटरियों के लिए भारत सरकार ने कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत तय कर रखे हैं। वास्तविकता यह है कि मप्र में अनेक लाटरियां इन सिद्धांतों के सरासर उल्लंघन की दोषी हैं। अनेक लाटरियां मप्र लाटरी नियंत्रण एवं कर अधिनियम—१९७३ की 'लाटरी' की प्रदत्त परिभाषा की चौखट में फिट नहीं बैठतीं। पोर्ते ने वित्तसचिव को इस आशय का सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार के सिद्धांतों के विपरीत यदि कहीं कोई लाटरी चलायी जा रही है, तो उसे बंद कर दिया जाये। अचरज की बात है कि

वित्तसचिव ने इस सुझाव को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया और मप्र के आंगन में निजी-लाटरियों की पौद फलती-फूलती रही।

यह अल्पबचत एवं लाटरी संचालनालय के अधिकारियों की लापरवाही ही थी कि करीब ४० लाख रुपए की राशि अधर में लटक गयी। प्रस्तुत: १९६९ से नवंबर, १९८३ तक मप्र शासन की लाटरियों का संचालन विभागीय तौर पर किया गया। नर्मदा साप्ताहिक के दसवें ड्रा दिनांक ४ नवंबर, १९८३ से उसका संचालन एजेंट के माध्यम से हुआ। मैसर्स एस पाल एंड कंपनी, कलकत्ता इसके पहले सोल सेलिंग एजेंट थे। ९७वें से १००वें ड्रा के टिकट लेने में आनाकानी करने पर ४ सितंबर १९८५ को उनका अनुबंध रद्द कर दिया गया। चूंकि, लगभग ८४ लाख रुपए कीमत के टिकट छपे पड़े थे और ड्रा रद्द करना संभव नहीं था, अत: वित्तसचिव की इच्छानुसार मैसर्स चंद्रा एजेंसीज, दिल्ली को तुरतफुरत नया एजेंट बनाया गया। विभागीय निर्देशों के अनुसार चार ड्रा की टिकटों की समतुल्य राशि में से दलाली (कमीशन) के बीस प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि की बैंक गारंटी एजेंट से ली जानी चाहिए थी। बारबार आग्रह पर चंद्रा एजेंसीज ने १५ लाख रुपए के ड्राफ्ट और १५ लाख रुपए की राष्ट्रीयकृत बैंक की गारंटी दी। शेष राशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की गारंटी के बजाय उन्होंने गाजियाबाद अर्बन कोआपरेटिव बैंक की गारंटी दी।

स्वरूप सिंह पोर्ते

बतौर संचालक पोर्ते ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार आर्गेनाईजिंग एजेंसी के आधार पर लाटरी चलाये। वह क्षतिपूर्ति के लिए लाटरी पर विक्रय कर लगाने के भी पक्षधर थे।

लाटरी संचालनालय और प्रकारांतर से सरकारी तंत्र में एजेंटों की घुसपैठ का परदाफाश जनवरी-फरवरी के घटनाक्रम से होता है। संचालक की अनुपस्थिति में लाटरी संचालन का काम उपसंचालक यूसी गुप्ता देख रहे थे। एजेंसी ने संचालक के अदालती पेशी के सिलसिले में कलकत्ता में होने का लाभ उठाया और पूर्व प्रदत्त १५ लाख रुपए के ड्राफ्ट का समायोजन उपसंचालक गुप्ता और अधीक्षक गिरीश सक्सेना के सहयोग से ड्रावार हिसाब के मद में करा लिया। उपसंचालक ने शासकीय हितों के विपरीत एक और काम यह किया कि ड्रावार हिसाब के मद में ४००५००० रुपए के ड्राफ्ट न लेकर उनके पेआर्डर ले लिये। यह गलती इतनी भारी पड़ी कि करीब चालीस लाख रुपए के लाभ के मद की यह रकम अदालत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद आज तक अप्राप्य है। एजेंसी ने कोआपरेटिव बैंक, गाजियाबाद और लाटरी संचालनालय, मप्र के अधिकारियों के सहयोग से मप्र सरकार को बहुत चालाकी से चूना लगा दिया।

मप्र शासन को लाखों रुपए की रकम से और हाथ धोना पड़ता, अगर पोर्ते पाल एजेंसी की ३६ लाख रुपए की रकम को 'इन्वोक' नहीं करते। बतौर संचालक पोर्ते ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकार आर्गेनाइजिंग एजेंसी के आधार पर लाटरी चलाये। वह क्षतिपूर्ति के लिए लाटरी पर विक्रय कर लगाने के भी पक्षधर थे। यह विडंबना ही है कि निजी लाटरियों के विरोध और सरकारी लाटरियों को जीवित रखने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद सरकारी लाटरी पोर्ते के काल में ही बंद हुई। उन्हें मन मसोसकर सरकारी लाटरी को बंद करने का फैसला करना पड़ा। इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि शासन ने उनकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया। उपसंचालक गुप्ता को निलंबित करने की उनकी सिफारिश शासन ने अमान्य कर दी। गुप्ता के खिलाफ विभागीय जांच मंथर गति से चलती रही। प्रमाण यह है कि आज भी गुप्ता शासकीय सेवा में निष्कंटक कार्यरत हैं।

समूचे प्रसंग में सर्वाधिक आश्चर्य तत्कालीन वित्तसचिव एमआर शिवरमन की भूमिका उपजाती है। सरकारी लाटरियों के विपरीत निजी लाटरियों के हितों की रक्षा की उनकी वृत्ति समझ से परे है। प्रश्न उठता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया ? क्या वह तत्कालीन मुख्यमंत्री को खुश करने और रिझाने के फेर में थे, ताकि कोई 'बड़ा पद' पा सकें ? और कुछ हुआ हो नहीं, परंतु इस सारे तमाशे का नतीजा यह हुआ कि सरकारी लाटरी ने दम तोड़ दिया और निजी लाटरियां, अनियमितताएं बरतने के बाद भी, फलतीफूलती रहीं। माना यह जाता है कि कानून और सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, परंतु जब यही हाथ शासकीय व लोकहितों के बजाय निजी हितों की पूर्ति का जरिया बन जायें, तो कोई भी विवेकवान प्राणी सिर धुनने के सिवा और क्या कर सकता है ?

—सुधीर सक्सेना

श्रीमती निर्मला बुच

प्रथम महिला गृह सचिव

श्रीमती निर्मला बुच दिल्ली से भोपाल लौट आयी हैं। मप्र की गृहसचिव बननेवाली वे पहली महिला आईएएस हैं। वे उस परिवार से संबंध रखती हैं, जिसने एक साथ तीन-तीन आईएएस मप्र को दिये। पूर्व वित्तसचिव जीएन बुच और गत लोकसभा चुनाव में बैतूल में हाकी के सितारा खिलाड़ी असलम शेर खां से लोहा लेनेवाले महेश नीलकंठ बुच भी इसी परिवार के हैं। श्रीमती बुच को तेजतर्रार और दबंग आला अफसरों में गिना जाता है और वे अपनी काबिलीयत का सुबूत अनेक विभागों में बखूबी दे चुकी हैं। बनारस हिंदू विवि से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद उनका विचार पीएचडी करने का था और उन्हें फेलोशिप भी मिल गयी थी, किंतु अचानक उनका मूड बना कि प्रशासनिक सेवा में जाया जाये। 'जहां चाह, वहां राह' की तर्ज पर वे १९६० में आईएएस हो गयीं। जबलपुर में पहली पदस्थापना के बाद वे देवास व उज्जैन में कलेक्टर रहीं और तदुपरांत सीढ़ियां चढ़ती हुई, वे अध्यक्ष, शिक्षा मंडल, शिक्षा सचिव, विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास व समाज कल्याण आदि पदों पर पहुंचीं। केंद्र सरकार में वे संयुक्त सचिव, समाज कल्याण, महिला ब्यूरो प्रमुख व संयुक्त सचिव इस्पात विभाग रहीं। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के बाद वे भोपाल लौटीं, तो मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने उन्हें गृहसचिव बना दिया। अपने प्रारंभिक दौर, संघर्षों और अनुभवों के बारे में कुछ अर्सा पहले 'माया' से उनकी लंबी बातचीत हुई थी। तब उन्होंने कहा था, "पुरुषप्रधान समाज में प्रारंभ से ही मुझे अपना रास्ता स्वयं तय करना पड़ा। रास्ता बनाने और जिम्मेदारी के पदों पर काम करने में मुझे कभी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। मैंने जब भी कोई दायित्व लिया, तो उसे पूरा किया और निरंतर ध्यान रखा कि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि महिला होने के कारण मैंने उसे नहीं किया या नहीं कर सकती थी।"

श्रीमती बुच के खाते में करीब तीन दशकों के काल में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। १९७२-७४ में जब वे शिक्षा मंडल में थीं, उन्होंने प्रशासन के विकेंद्रीकरण और केंद्रीय मूल्यांकन की प्रणाली प्रारंभ की। १९७५-७६ में विशेष सचिव, वित्त के पद पर काम के दरम्यान शासकीय कर्मियों के सामूहिक बीमे के लिए परिवार लाभ योजना बनाकर लागू करायी। रेशम-उद्योग के लिए नये संचालनालय और महिला एवं बाल विकास संचालनालय की स्थापना में उनकी महती एवं सर्वप्रमुख भूमिका रही। अब देखना यह है कि फ्रेंच एवं जर्मन भाषाओं में डिप्लोमाधारी मादाम बुच बतौर गृह सचिव क्या कर दिखाती हैं? ■

जनता दल

अंतर्कलह की चपेट में

विद्याचरण शुक्ल

मध्यप्रदेश में जनता दल को अस्तित्व में आये हुए जुम्मा-जुम्मा आठ रोज हुए हैं, लेकिन जनतादल अभी से असंतोष और अंतर्कलह की चपेट में है और उसके पांव बिखराव व विखंडन की ओर अग्रसर हैं। पार्टी में एक ही घटक के वर्चस्व ने जो क्षोभ पैदा किया है, उसका लावा कभी भी फूट सकता है। मप्र में जद के तीन घटकों—जनता पार्टी, जनमोर्चा और लोकदल में से केवल जनता पार्टी ही ऐसी है, जिसका प्रदेश में थोड़ा-बहुत प्रभाव है और जिसका राज्य विधानसभा में अपना पृथक अस्तित्व है। लोकदल के इकलौते विधायक रमाशंकर सिंह के कांग्रेस-इ में जाने के बाद लोकदल मप्र में अस्तित्वहीन हो गया था और पिछले चुनाव में प्रदेशभर में चुनाव लड़ने के बाद भी वह खाता खोलने में विफल रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौरों और विद्याचरण शुक्ल की सक्रियता से यह उम्मीद बंधी थी कि असंतुष्ट इंकाजन मोर्चे में शरीक होंगे। मगर यह उम्मीद मृगतृष्णा सिद्ध हुई, लिहाजा मोर्चा कभी भी आधी हकीकत, आधा फसांना से आगे नहीं बढ़ सका। सारांश यह कि मप्र में जद का अस्तित्व मुख्यतः पूर्ववर्ती जनता पार्टी के जनाधार और उसकी सक्रियता के पाये पर टिका हुआ है।

द्वंद्व : जनता दल का गठन हुआ, तो उसके अध्यक्ष का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। प्रांतीय अध्यक्ष पद के दावेदारों में तीन प्रमुखतम प्रत्याशी थे, सांसद विद्याचरण शुक्ल, पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम कौशिक और पूर्व सांसद यमुना प्रसाद शास्त्री। यह पहला मौका था कि एक दशक के अंतराल में तीन बार एक दूसरे का चुनावी-सामना कर चुके विद्याचरण और कौशिक नाटकीय घटनाक्रम के फलस्वरूप एक ही मंच पर थे। जब अध्यक्ष चुनने का मौका आया, तो दिल्ली में कूटनीति का दौर चला। वीसी का लियाजां रंग लाया। अरुण नेहरू ने वीसी शुक्ल का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन इतने से बात बनी नहीं। वीपी सिंह दुविधाग्रस्त थे। उन्हें इससे उबारा बीजू पटनायक ने, जिन्होंने अप्रत्याशित तौर पर वीसी का समर्थन कर डाला। रामकृष्ण हेगड़े और मधु दंडवते की चुप्पी ने रही-सही कोर-कसर पूरी कर दी। परिणामस्वरूप विद्याचरण आंतरिक विरोध के बावजूद जद के अध्यक्ष हो गये।

मप्र जद के अध्यक्ष पद पर वीसी की नियुक्ति कौशिक और शास्त्री-सरीखे पुराने समाजवादियों की पहली कूटनीतिक पराजय थी। उन्हें एक और करारा आघात तब लगा, जब रघु ठाकुर ने भीतर-ही-भीतर विद्याचरण से हाथ मिला लिया। आंतरिक द्वंद्व में जगदीश जोशी ने भी विद्याचरण-रघु ठाकुर-धुरी का साथ दिया। परिणाम यह हुआ कि पुरुषोत्तम कौशिक, बाबू जबर सिंह, लक्ष्मीनारायण नायक और नारायण शंकर त्रिवेदी जैसे नेताओं को जद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ठौर नहीं मिला। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि रघु ठाकुर को हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का स्नेह और विश्वास प्राप्त है और इसी के बल पर वे जद के राष्ट्रीय महामंत्री बनने में सफल रहे।

उपेक्षा और असंतोष : पूर्ववर्ती जपा घटक के नेताओं के इस आशय के तर्क में दम है कि सर्वप्रमुख घटक होने के बाद भी मप्र में जद में उसे कोई श्रेय या महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। उलटे उनकी उपेक्षा की गयी और उनके साथ सौतेला व अपमानजनक सलूक किया गया। अनेक नेताओं से बातचीत में इसका एक वरिष्ठ नेता ने बेबाक खुलासा किया। तदनुसार तीन घटकों में से मोर्चे को जहां अध्यक्ष का पद मिला, वहीं लोकदल को राष्ट्रीय महामंत्री पद। जपा घटक को मन मसोस कर रह जाना पड़ा। हाल में चुनाव समिति के अध्यक्ष के चयन का प्रश्न आया, तब भी शुक्ल-ठाकुर लाबी ने शीर्ष स्तर पर जपा के बजाय अपने मनपसंद व्यक्ति को इस पद पर बिठाने की कोशिश की। 'माया' के सूत्रों के अनुसार वीसी इस पद पर परिदृश्य से बरसों पहले ओझल हो चुके पूर्व सांसद नारायण चौधरी को नियुक्त कराने की फिराक में हैं। इसके विपरीत जपा घटक इस पद पर तेजतर्रार जनता विधायक प्रेमलाल मिश्र को लाना चाहता है। इसी क्रम में सेक्रेट्री जनरल पद के लिए भी द्वंद्व जारी है। पता चला है कि जगदीश जोशी और रघु ठाकुर ने इस पद के लिए क्रमशः झाबुआ के भागीरथ भंवर और इंदौर के मोहन डाकोनिया का नाम प्रस्तावित किया है।

प्रेमलाल मिश्र

नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव

मतभेद : जद के विभिन्न घटकों में मतभेद अब ढंकामुंदा कतई नहीं है। गाहे-बगाहे वह उजागर हुआ है। वीसी को अध्यक्ष बने दो माह से अधिक समय हो गया, मगर वह अभी तक प्रांतीय कार्यसमिति की घोषणा नहीं कर सके हैं। इसके आसार कम हैं कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे। बताया जाता है कि वीसी द्वारा प्रस्तुत सूची दिल्ली में शीर्षस्थ नेता एकाधिक बार रद्द कर चुके हैं। कारण यह कि वे एकतरफा चल रहे हैं और जद में मोर्चे का वर्चस्व चाहते हैं। वीसी के हठ का आलम यह है कि ग्वालियर में उनके कट्टर अनुयायी तक काफी पहले उनका साथ छोड़ गये हैं। उन पर एक आरोप यह भी है कि वे जद का अस्तित्व रायपुर-महासमुंद में केंद्रित करने पर आमादा हैं। जद नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा वीसी के रवैये से नाखुश हैं और वीसी की पसंद को शक की नजर से देखते हैं। यही मनःस्थिति पुरुषोत्तम कौशिक की भी है। बताते हैं कि इन दोनों नेताओं ने आंतरिक तौर पर शुक्ल के विरोध में हाथ मिला लिया है और क्रमशः मध्यभारत और छत्तीसगढ़ की कमान संभाल ली है। इंका व भाजपा नेता जद के इस अंतर्द्वंद्व को उत्सुकता से देख रहे हैं और वे क्षुब्ध कौशिक पर डोरे डालने की फिराक में हैं। पुराने समाजवादियों में इस बात को लेकर भी असंतोष है कि मप्र में जद की बागडोर ऐसे आदमी को सौंप दी गयी है जो देश में इमरजेंसी के दौरान ज्यादतियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा है और जिसकी छवि इमरजेंसी में चौकड़ी में शामिल रहने के कारण अच्छी नहीं है।

जद के विभिन्न घटकों में मुद्दों और फैसलों पर मतैक्य न हो पाना भी जद के लिए सुखद नहीं कहा जा सकता। दुर्ग में उपचुनाव में मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को वाकओवर देने के फैसले को जद के सामूहिक निर्णय के बजाय मुख्यतः वीसी का थोपा हुआ निर्णय माना जा रहा है। जद के शीर्ष नेताओं की यह आशा भी धूल में मिल चुकी है कि वीसी मप्र, विशेषकर छत्तीसगढ में असंतुष्ट इंकाजनों को जद में लाने में सफल होंगे।

इन तमाम बातों के बाद भी यह जिज्ञासा मायने रखती है कि आगामी चुनाव में मप्र में जनता दल की क्या भूमिका व अहमियत होगी ? जद के अधिकांश नेता जो कल तक भाजपा को अछूत मानते थे, अब भाजपा से व्यावहारिक तालमेल के पक्ष में हैं। फिलहाल मप्र विधानसभा में जद के पांच विधायक हैं और वे अपने होने का अहसास कराने में सफल रहे हैं। भाजपा के कैलाश जोशी के सकारात्मक बयानों व रुख से जद व भाजपा में तालमेल व समझौते की संभावनाएं बढ़ी हैं। प्रेमलाल मिश्र, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव और जगदंबाप्रसाद निगम आदि जद नेता मानते हैं कि जद व भाजपा में समुचित तालमेल मप्र में विपक्षी सरकार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। फिलहाल न तो इससे इनकार किया जा सकता है कि मप्र में भाजपा व जद में समझौते के उजले आसार हैं और न ही इसे इनकार किया जा सकता है कि प्रदेश में विपक्षी सरकार का सपना देखनेवाली जद स्वयं मतभेदों व अंतर्कलह की शिकार है। जद नेता व विधायक प्रेमलाल मिश्र कहते हैं, "हम मप्र में जद को किसी की जागीर नहीं बनने देंगे।" प्रेमलाल किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन उनका कटाक्ष किस पर है, इसे राजनीति की बारहखड़ी का जानकार कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से समझ सकता है।

—एसपी त्रिपाठी

अंबेडकर विश्वविद्यालय

हरिजनों के लिए चुनावी चुग्गा

आम चुनाव के करीब आने पर ही लखनऊ में भीमराव अंबेडकर आवासीय विश्वविद्यालय की आधारशिला क्यों रखी गयी? इस समारोह में जो घोषणाएं हुई हैं, उनसे क्या हाथ से निकलते जा रहे हरिजन मतदाताओं का दिल जीत पाने में कांग्रेस-इ कामयाब हो पायेगी?

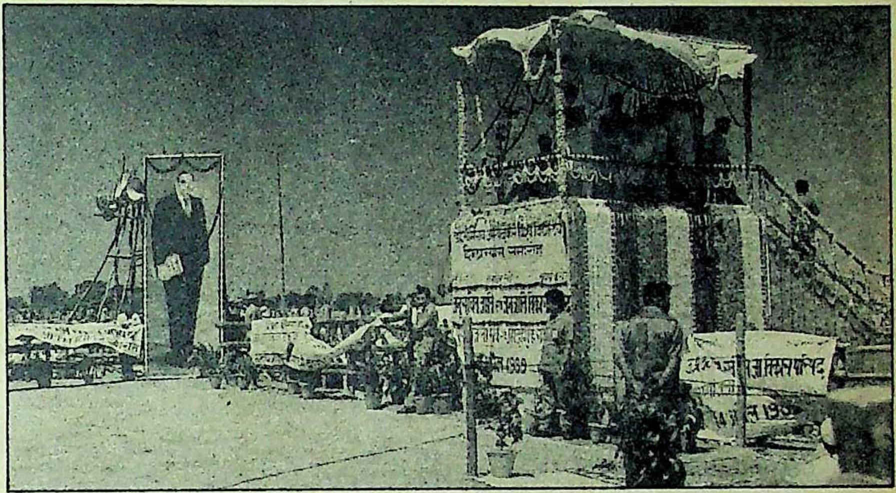

वायदे-ही-वायदे: अंबेडकर विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह का मंच

एक मोटे अनुमान के तहत सभी यह मान रहे हैं कि ८९ का अंत होते-होते आम चुनाव होने हैं। फिर इस बात के संकेत तो ८९-९० के बजट से ही मिल गये थे, जिसमें आंकड़ों का उलटफेर करके नरमी पैदा करने की कोशिश की गयी थी। यही वजह है कि आजकल प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे चुनावी लालीपाप माना जा रहा है। १४ अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रायबरेली रोड पर दलितों के मसीहा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की उनके द्वारा आधारशिला रखना भी उनके चुनावी अभियान का अंग माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि डा० अंबेडकर के जन्मदिवस पर अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव रखने के साथ ही राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया था। यह सम्मेलन परिषद के अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गुलाब सेहरा की उपज था।

रुख मोड़ने का प्रयास: राजनीतिक दिग्गजों का मानना है कि कांशीराम से प्रभावित दलितों का झुकाव जिस तेजी से डीएस-४ तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर हुआ है, उसे कांग्रेस अपने लिये बड़ा खतरा मानती है। फिर कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक से मुस्लिम पहले ही खिसक चुके हैं। ऐसे में हरिजनों के बिना चुनाव जीतना कांग्रेस असंभव मानती है। शायद यही वजह है कि हरिजनों को रिझाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उत्तर प्रदेश से इस प्रकार के आयोजनों की मुहिम शुरू की गयी है। चूंकि गुलाब सेहरा ही कांग्रेस में एक मात्र ऐसे हरिजन नेता हैं, जिनके पास प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद के कार्यकर्ता हैं, अतः उस कार्य के लिए उन्हें ही चुना गया। गुलाब सेहरा इसके पूर्व भी ८ अक्तूबर '८३ को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में परिषद के नाम पर दलितों का एक सम्मेलन कर चुके थे। उसमें भी राजीव गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से भाग लिया था।

जहां तक डा० अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय के वजूद में आने की बात है, सूत्रों का कहना है कि यह गुलाब सेहरा के प्रयास की ही परिणति है। दरअसल, गुलाब सेहरा खुद एक हरिजन सम्मेलन कराने के इच्छुक थे। मार्च के प्रथम सप्ताह में उन्होंने मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से इस संबंध में गुफ्तगू भी की थी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री तक बात पहुंचायी, तो गुलाब सेहरा को प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। सेहरा, प्रधानमंत्री के दिमाग में यह बात बिठाने में सफल रहे कि डा० अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय और हरिजनों के लिए कुछ घोषणा करने का हरिजनों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे जहां एक ओर कांशीराम का प्रभाव कम होगा, वहीं कांग्रेस के प्रति हरिजनों में विश्वास जागेगा, जिसका सीधा असर आम चुनाव पर पड़ेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि सेहरा चाहते थे कि विश्वविद्यालय आगरा में बने, क्योंकि आगरा दलितों का गढ़ है।

जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बलराम सिह यादव को पता चला कि गुलाब सेहरा ने मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से मिलकर सम्मेलन में राजीव गांधी को आने के लिए तैयार कर लिया है, तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि केंद्रीय संचार मंत्री वीर बहादुर सिंह ने यादव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया था, ताकि वह नारायण दत्त तिवारी की काट कर सकें। पर बलराम सिह यादव ने अध्यक्ष बनने के बाद शुरू में मुख्यमंत्री से हाथ मिलाकर वीर बहादुर के विरोधियों को बढ़ावा दिया। फिर वे मुख्यमंत्री तिवारी की कुरसी पाने के सपने देखने लगे। उल्लेखनीय है कि इसी दौरान यह बात भी उठी थी कि किसी हरिजन को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने से चुनाव में कांग्रेस हरिजन वोट पाने में सफल हो सकती है तथा उस समय गुलाब सेहरा का नाम उभर कर सामने आया भी था। बस इसी खतरे से भयभीत होकर बलराम सिह यादव ने गुलाब सेहरा द्वारा आयोजित सम्मेलन को विफल बनाने के लिए अंदर-ही-अंदर काफी प्रयास किये। उनका मंशा यह था कि सम्मेलन विफल होगा, तो सेहरा की राजीव गांधी के समक्ष किरकिरी हो जायेगी तथा उन पर मंडरा रहा खतरा टल जायेगा। इसी अभियान के तहत बलराम सिह यादव ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारियों से यहां तक कहा कि परिषद के नाम पर आयोजित सम्मेलन कांग्रेस का नहीं, गुलाब सेहरा का व्यक्तिगत सम्मेलन है।

चुनावी लालीपाप: अंततः खींचतान के बीच प्रस्तावित डा० भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्रय किये गये मैदान पर १४ अप्रैल को अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद का सम्मेलन शुरू हुआ। हालांकि गुलाब सेहरा चाहते थे कि सम्मेलन बेगम हजरत महल पार्क में हो, किंतु प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकारों ने अनुमति नहीं दी। उनका कहना था कि जहां विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाये, वहीं खुला सम्मेलन आयोजित कर लिया जाये। मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का भी यही सोचना था कि यदि विश्वविद्यालय की भूमि पर सम्मेलन किया जाये, तो हरिजन भी देख सकेंगे कि विश्वविद्यालय की जमीन वास्तव में ली गयी है।

प्रधानमंत्री के सम्मेलन में पहुंचने का समय सुबह ग्यारह बजे तय हुआ था, किंतु न जाने क्या अड़चन बीच में आ गयी कि ऐन मौके पर समय बदल कर साढ़े दस कर दिया गया और प्रधानमंत्री नियत समय से पहले ही सम्मेलन स्थल पर पहुंच गये। परिणामस्वरूप बाहर के जिलों से जो हरिजन प्रधानमंत्री को देखने व सुनने आये थे, उनमें से

दो यादव एक साथ : बलराम और रामनरेश

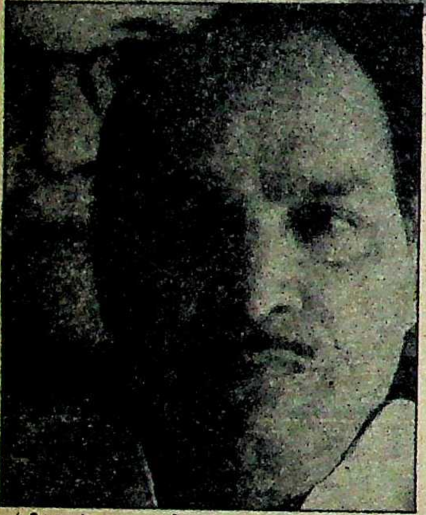

ऊंची छलांग : गुलाब सेहरा

अधिसंख्य ने या तो प्रधानमंत्री को लौटते देखा या वे सम्मेलन स्थल तक पहुंच ही नहीं पाये।

बहरहाल, सम्मेलन स्थल पर आये हरिजनों को संबोधित करते हुए राजीव गांधी ने जितनी भी घोषणाएं कीं उनका मकसद आगामी चुनाव के लिए हरिजनों को रिझाना था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा, "कांग्रेस १९९० के बाद भी हरिजनों के लिए संविधान में व्यवस्था करेगी। आरक्षण नीति की कमियां दूर करके उस पर कड़ाई से पालन किया जायेगा। लोकसभा तथा विधानसभा की तरह पंचायती राज संस्थाओं में भी अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जायेगा तथा जवाहर रोजगार योजनाओं में भी ३० प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जायेगा।"

उल्लेखनीय है कि जनवरी, १९९० में संविधान में प्रदत्त आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में जातिगत आधार पर आरक्षण की बात कह चुकी है। शायद इसी कारण १९९० के बाद भी १० वर्ष के लिए संविधान में आरक्षण की घोषणा करके राजीव गांधी ने निश्चित तौर पर हरिजनों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बिठाया है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने जनता दल और नेशनल फ्रंट को भी आरक्षण विरोधी करार दिया। वे यह बताने से नहीं चूके कि किस प्रकार जनता पार्टी ने अपने शासन काल में आरक्षण जारी रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, जबकि श्रीमती गांधी ने सत्ता में आते ही पहला कार्य, अगले दस वर्ष तक आरक्षण जारी रखने का किया था। पंचायत राज व्यवस्था में भी आरक्षण नीति लागू करने का यही मंशा था, ताकि ग्रामीण अंचलों तक कांग्रेस का स्वरूप हरिजन समर्थक के रूप में उभर सके। अमेठी चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों का जिम्मा जिन लोगों पर है, उन पर भी राजीव गांधी ने यह कह कर कटाक्ष किया, "इस विश्वविद्यालय का भवन बहुत मजबूत बनना चाहिए। वैसे भवन नहीं जैसे मेरे चुनाव क्षेत्र में बने हैं जो बनते ही ढहने लगे हैं।"

आपसी मनमुटाव : प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने १४ अप्रैल के लखनऊ दौरे में हरिजनों को रिझाने के लिए जो घोषणाएं कीं उनसे आगामी चुनाव में कांग्रेस-इ को कितना लाभ मिलेगा यह तो अलग बात है, किंतु उक्त सम्मेलन में राजनीतिक दृष्टि से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जिनको देख-जानकर कांग्रेस-इ की आंतरिक स्थिति का जायजा मिलता है। प्रधानमंत्री ने हाल में ही जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव को स्वयं मंच पर बुलवाया और विचार व्यक्त करने को कहा। रामनरेश यादव ने अपने छोटे से भाषण के दौरान कहा, "मैं स्वेच्छा से कांग्रेस में शामिल हुआ हूं।" इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रहा राजीव गांधी के समक्ष, वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी के बीच चल रहे शीतयुद्ध का, खुलकर सामने आना। हुआ यह कि जब वीर बहादुर सिंह को भाषण देने को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा, "मैंने इस अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए २५ लाख रुपए का अनुदान डेढ़ वर्ष पूर्व १९८७ में आगरा में हुई रैली के दौरान दे दिया था।" यही नहीं, उन्होंने यह तुक्का भी जड़ दिया, "जब तक मैं प्रदेश में सीएम था, मैंने देखा कि हरिजनों पर कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा है।" इसके पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन में वीर बहादुर सिंह कह चुके थे, "मैंने अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किये थे, उनमें से कुछ को रोक दिया गया है और कुछ के क्रियान्वयन में जानबूझकर देरी की जा रही है।"

मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी उसी समय से जले भुने बैठे थे। राजीव गांधी के समक्ष वीर बहादुर सिंह के कटाक्ष ने आग में घी का काम किया। जब नारायण दत्त तिवारी को बोलने का मौका मिला, तो वीर बहादुर की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "आगरा में किसी ने जो दिया होगा, वह २५ लाख अलग है। उसका इस अंबेडकर विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं। मैंने आगरा में अंबेडकर टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट के लिए ५० लाख रुपए अलग से दिये है और आज यह घोषणा करता हूं कि मेरठ में भी डा० अंबेडकर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जायेगी।" अपने भाषण के बीच ही मुख्यमंत्री ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के लिए १५ लाख मकान बनाये जाने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि ११० करोड़ की लागत से बननेवाला अंबेडकर विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसके लिए २०० एकड़ जमीन पहले ही ढाई करोड़ रुपए देकर खरीदी जा चुकी है। मजे की बात यह थी कि नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह के इस टकराव पर प्रधानमंत्री मुस्कराते देखे गये।

असली मकसद : जब 'माया' ने गुलाब सेहरा से यह प्रश्न किया कि आखिर अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में हरिजनों का सम्मेलन कराने का मकसद क्या था ? तो वे बोले, "जिस प्रकार डीएस-४ चोट कर रहा है उससे लड़ने के लिए यह करना बहुत जरूरी है।" वैसे यह भी सच है कि गुलाब सेहरा वीर बहादुर सिंह से काफी नाराज हैं। उन्होंने 'माया' को बताया, "पहले तो ६ दिसंबर '८७ को वीर बहादुर सिंह ने आगरा के अंबेडकर पार्क में जाकर अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किये बिना लौटकर उनका अपमान किया था। उनके अनुनय विनय पर मैंने अंबेडकर के अनुयायियों को समझा-बुझाकर उनकी सभा करवायी थी। अन्यथा हरिजन आगरा में कांग्रेस की सभा आयोजित न होने देने की कसम खा चुके थे। उसी दौरान वीर बहादुर सिंह ने आगरा में अंबेडकर इंस्टीट्यूट के लिए २५ लाख रुपए देने की घोषणा की थी। यह मात्र घोषणा ही रही। जब तक वह मुख्यमंत्री रहे उन्होंने यह धनराशि नहीं दी। अभी हाल में नारायण दत्त तिवारी ने ५० लाख रुपए आगरा के इंस्टीट्यूट के लिए जरूर दिये हैं।"

—निशीथ जोशी

छाया : मनमोहन शर्मा

बेडकर
नुदान
दौरान
भी जड़
खा कि
ा है।"
में हुए
ह चुके
म शुरू
हैं और
ा रही

समय
ह वीर
काम
ने का
ब देते
दिया
बेडकर
गरा में
लाख
करता
ट की
च ही
रिजनों
णा भी
गत से
ऐसा
जमीन
की है।
ी और
नमंत्री

सेहरा
ी पर
कसद
चोट
बहुत
ा वीर
' को
हादुर
डकर
उनका
मैंने
उनकी
रा में
म खा
रा में
ने की
तक
दी।
लाख
हैं।"
ोशी
शर्मा

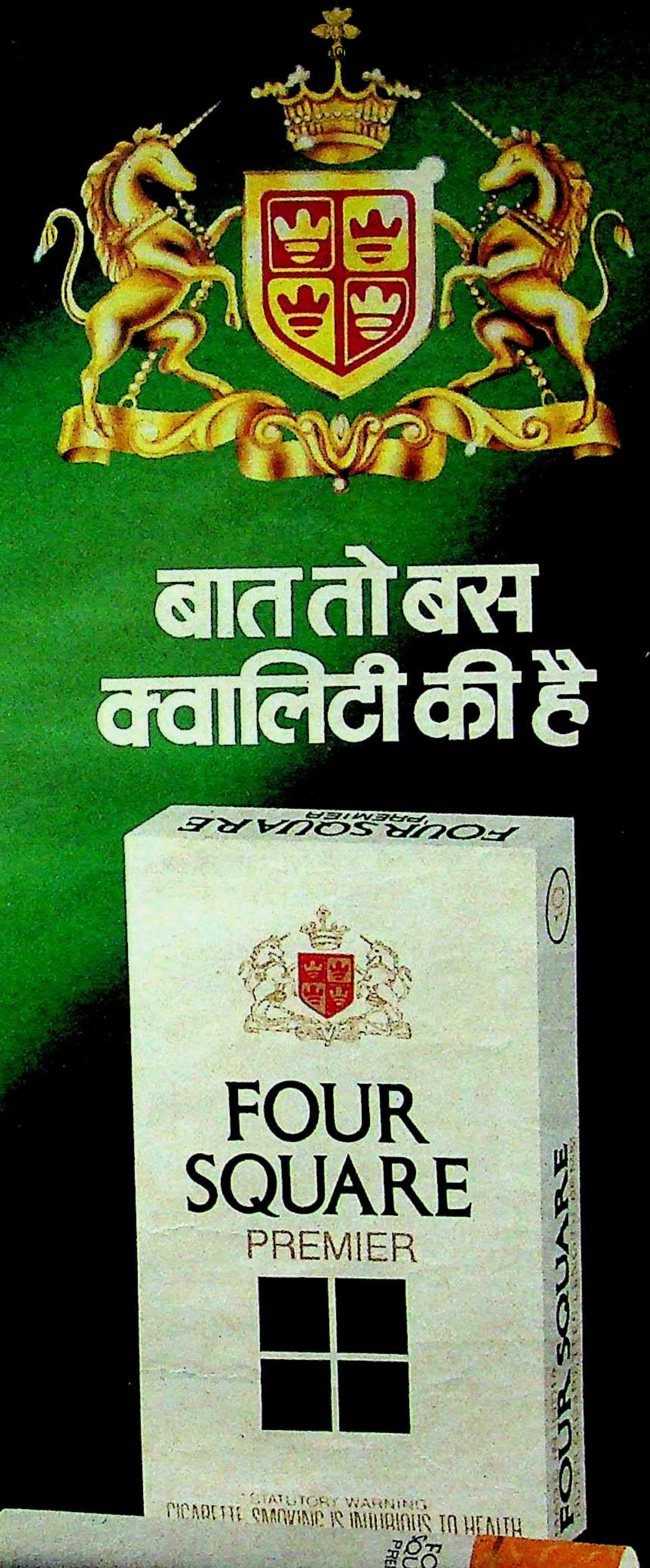

बात तो बस
क्वालिटी की है
FOUR SQUARE
PREMIER
FOUR SQUARE
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
FOUR SQUARE PREMIER

रु. 3.50 में 10 स्थानीय कर अतिरिक्त

वैधानिक चेतावनी : सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
STATUTORY WARNING : CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

सबसे अलग
सबसे सुहाना
JCT FABRICS

CC-0. In Public Domain. Guru [illegible] Colle

The Thapar Group

डाक्टर साहब

एक आदर्श डाक्टर की कहानी है !

डाक्टरी पेशे और अस्पताल की जिंदगी से जुड़े अनेक पहलुओं को लेकर बने सीरियल 'जीवन रेखा' के बाद अब दूरदर्शन पर उसी से मिलता-जुलता टीवी सीरियल 'डाक्टर साहब' प्रदर्शित हो रहा है। 'जीवन रेखा' एक अस्पताल के डाक्टर, हाउसजाब के लिए आनेवाले नये डाक्टरों, वहां की अंदरूनी व्यवस्था तथा मरीजों की जिंदगी, उनके साथ डाक्टरों-नर्सों, अस्पताल के कर्मचारियों आदि के व्यवहार और संबंधों की कहानी है, जबकि 'डाक्टर साहब' में केवल एक डाक्टर और उसके जीवन में आनेवाले अलग-अलग तरह के मरीजों, अलग वर्ग, अलग किस्म के इंसानों तथा विभिन्न पेशों से संबंधित लोगों की समस्या व जिंदगी को पेश किया गया है। इस सीरियल में डाक्टर के साथ मरीजों का जो संबंध है, वह डाक्टर-मरीज के अलावा अपनत्वभरा भी है। वह उनका शारीरिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी इलाज करता है।

इस सीरियल में मानवीय भावना उभारने की पूरी कोशिश है।

'डाक्टर साहब' के दृश्य में जावेद खान, समीर खख्खर और परीक्षित साहनी

पूरे सीरियल में कथानक से सीधे जुड़ने वाले पात्र हैं।

हर शृंखला में दो या तीन विपरीत स्वभाववाले मरीज एक ही समय में डाक्टर के पास आते हैं, उनको किस प्रकार के उपचार और व्यवहार की आवश्यकता है, इसे वह डाक्टर अच्छी तरह समझता है। 'डाक्टर साहब' के पहले हृषिकेश मुखर्जी ने भी 'हम हिंदुस्तानी' में एक डाक्टर (अशोक कुमार) की जिंदगी व लोगों के साथ उसके संबंधों-ताल्लुकात को दर्शाया था।

लीक से हटकर : 'डाक्टर साहब' एक ऐसा किरदार है, इस सीरियल में जो आदर्श डाक्टर की प्रतिमूर्ति है। आमतौर पर डाक्टर कहने से हमारे जेहन में जो एक ग्लैमरस डाक्टर की छवि बनती है, वह उस छवि से अलग है। वह (परीक्षित साहनी) एक जनरल प्रैक्टिशनर है, एक गली के नुक्कड़ पर उसका छोटा-सा क्लीनिक है, वह अपने रोगियों की जिंदगी में पूरी तरह 'इन्वाल्व' हो जाता है। वह अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता। उसकी पत्नी (रोहिणी हटंगड़ी) शिकायत करती रहती है, कुछ-न-कुछ मांग करती रहती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान अपनी पत्नी की बातों पर न देकर अपने इरादों पर अडिग रहता है।

इस शृंखला के सभी तेरह एपीसोडों की कथा अलग-अलग है। हर एपीसोड में एक या दो मरीज आते हैं, जिनके द्वारा कहानी बतलायी जाती है। जैसे एक अमीर महिला (शम्मी) जिसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक परेशानी की वजह से वह स्वयं को बीमार महसूस करती है और बड़ी जल्दी घबड़ा जाती है। वह समझती है कि उसे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी तरफ एक मेहनत-मजदूरी करनेवाला वृद्ध मजदूर (एके हंगल) है, जिसे काफी चोट लगी है, लेकिन उसके पास इतनी फुरसत नहीं कि अपनी चोटों पर ध्यान दे। उसे तो अपनी रोजी-रोटी कमाने की चिंता है। इतनी गंभीर चोट को भी वह मामूली समझ कर अपनी जिंदगी जीना चाहता है। इसी तरह हर एपीसोड में एक ही वक्त पर दो मुखतलिफ मरीज आते हैं। समीर खख्खर ('नुक्कड़' का खोपड़ी) एक ऐसा मरीज है, जिसे हर वक्त लगता है कि उसे कोई-न-कोई बीमारी अवश्य है। वह किसी पत्रिका में यदि ब्रेन ट्यूमर के बारे में पढ़ता है, तो उसे लगने लगता है कि उसे भी ब्रेनट्यूमर है। वह डाक्टर को रास्ते में भी मिल जाता है, तो वहीं शुरू कर देता है, 'डाक्टर, मेरी नब्ज देखो, कितनी तेज चल रही है।'

एक एपीसोड में विदेश में रह रहे इसी डाक्टर के मित्र डाक्टर (सईद जाफरी) की कहानी है, जिसे वहां हर तरह की सुख-सुविधा प्राप्त है। जब वह छुट्टियां बिताने भारत आता है, तो उसे यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोनों का इस पेशे के बारे में नजरिया और सोच कितना अलग है, इसे इस सीरियल में बखूबी दर्शाया गया है।

एक कड़ी में परिवार-नियोजन को लेकर भी विपरीत असर दिखलाया गया है। इसी तरह एक एपीसोड में एक भ्रष्टाचारी डाक्टर का इस डाक्टर से वास्ता पड़ता है, जिसके कारण इसकी आदर्शवादी 'इमेज' प्रभावित होती है, जो उसकी अब तक की कमाई हुई पूंजी है। तब यह डाक्टर उसका पता लगाता है और उस डाक्टर को 'एक्सपोज' करता है।

पूरे सीरियल में कथानक से सीधे जुड़नेवाले पात्र हैं—डाक्टर साहब (परीक्षित साहनी), उनकी पत्नी (रोहिणी हटंगड़ी), कंपाउंडर (जावेद खान) और डाक्टर साहब की पुत्री (अमृता)। बाकी सभी कलाकार हर कड़ी में कहानी के मुताबिक बदलते रहते हैं। समीर खख्खर को तीन-चार कड़ियों में दोहराया गया है।

इस शृंखला का निर्माण किया है, पामेला चोपड़ा (पहला सीरियल 'खजाना') ने तथा निर्देशन और कहानी परीक्षित साहनी की है, जो डाक्टर साहब की मुख्य भूमिका में भी हैं। परीक्षित साहनी, हालांकि रूस से निर्देशन का कोर्स करके आये थे, परंतु यह उनका प्रथम प्रयास है। इस सीरियल की निर्मात्री पामेला चोपड़ा का कहना है, "वे अभिनेता और डायरेक्टर से भी कहीं ज्यादा एक अच्छे लेखक हैं।"

इस सीरियल के बारे में परीक्षित साहनी कहते हैं, "हम दर्शकों को कोई उपदेश नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यह जरूर बतलाना चाहते हैं कि डाक्टर महज चीर-फाड़ करने, भारी-भरकम फीस वसूलनेवाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह पहले एक इंसान है—दोस्त, मार्गदर्शक और सहायक। आप किस तरह उसका सही उपयोग कर पाते हैं, यह आप पर निर्भर है। इस सीरियल में हमने मानवीय भावना उभारने की पूरी कोशिश की है।"

—बंबई ब्यूरो

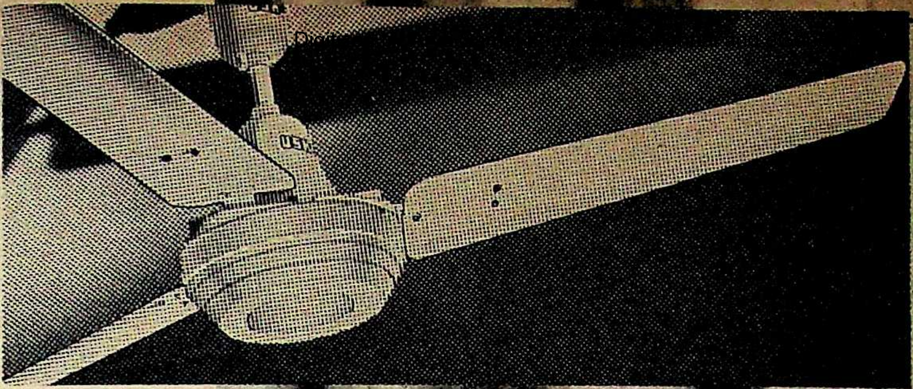

USHA

स्टैला

उषा का अंदाज़!

सुंदर रूप-रंग, दिलकश अंदाज़।
मोतियों-सा सफ़ेद और
दमकता हुआ भूरा।
डबल बॉल बेयरिंग-युक्त।
उषा की 40 वर्षों से अधिक की
उत्कृष्ट तकनीक से रचा।

आपका अंदाज़!

आज 2.73 करोड़ से भी अधिक
उषा पंखों के संतुष्ट ख़रीदार
भारत में और विश्व के
60 देशों में फैले हैं।
उषा पंखें—सीलिंग, टेबल, पेडेस्टल,
वॉल, कैबिन और एग्ज़ॉस्ट पंखों
की विस्तृत रेंज में।
इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
को भरोसा है उषा पर।

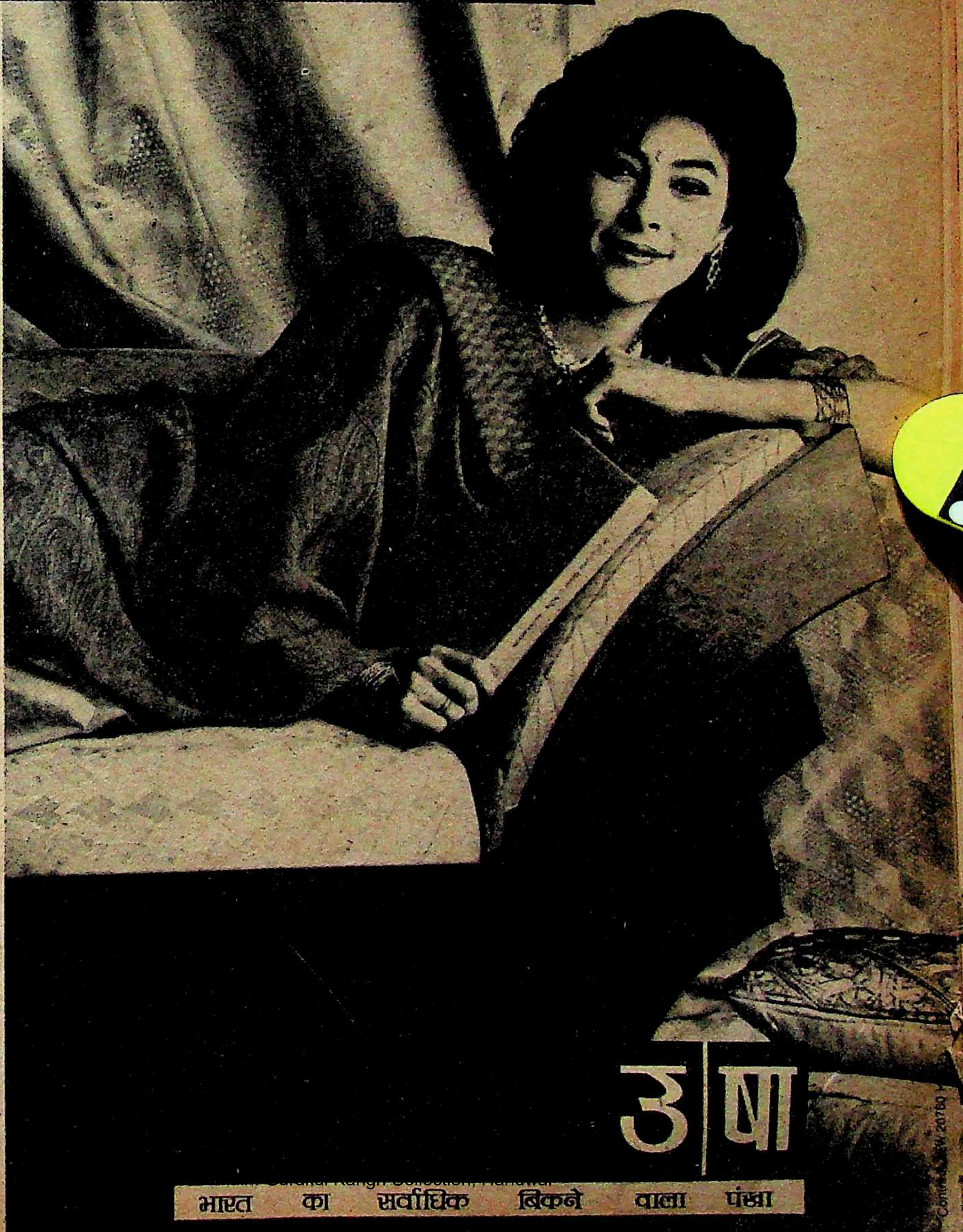
उषा
भारत का सर्वाधिक बिकने वाला पंखा

Gurukul Kangri Collection, Haridwar

इमरान खान

तलाश एक अदद बीवी की

क्रिकेट के सितारों से शादी करने के लिए तो फिल्मी परदे की शोख हसीनाएं तक बेताब रहती हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि विश्व क्रिकेट के आलराउंडर इमरान खान ३५ वसंत पार करने के बावजूद एक अदद बीवी के लिए तरस रहे हैं?

कौन यकीन करेगा कि क्रिकेट के मैदानों पर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर लाखों दर्शकों को चकाचौंध करके अपना प्रशंसक बना लेनेवाले विश्व क्रिकेट के चोटी के आलराउंडर इमरान खान अपने जीवन के पैंतीस वसंत पार कर चुकने के बाद न सिर्फ कुंआरे हैं, बल्कि शादी की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। इमरान खान के फैन, जो इमरान की जिंदगी को करीब से देखकर उनकी हर अदा का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, भी उनके अविवाहित रहने से काफी मायूस रहते हैं, किंतु बेचारे कर भी क्या सकते हैं? अकसर यह भी देखा गया है कि इमरान के प्रशंसक शादी के मसले पर इमरान की आलोचना करते हैं। इमरान को विवाह के लिए प्रेरित करनें के लिए उनके फैन यह कहते नहीं थकते कि अभी इमरान की उम्र ही क्या है? आज भी वे मन बना लें, तो एक-से-एक हसीन लड़की उनकी बीवी बनने के लिए तैयार हो जायेगी। किंतु अफसोस इस बात का है कि इमरान के प्रशंसक भी यह नहीं जानते कि इमरान के समक्ष सवाल उनकी उम्र का नहीं। असलियत तो यह है कि पाकिस्तानी संस्कृति इमरान की मजबूरी बन गयी है, जिसके चलते आक्सफोर्ड में शिक्षित क्रिकेट खिलाड़ी धर्मसंकट में फंसा है। इस संबंध में इमरान खुद बताते हैं, "जाहिर है मैं उम्र के जिस मोड़ पर पहुंच गया हूं वहां पाकिस्तानी रस्म के हिसाब से शादी नामुमकिन है। फिर मैंने पाकिस्तान में ही जिंदगी गुजारने का भी तो फैसला किया है। ऐसे में किसी मगरिबी (पश्चिमी) दुल्हन का मिलना भी मुमकिन नहीं। जबकि यह भी सच है कि इमरान के दक्षिण केंसिग्टन (लंदन) स्थित छोटे से मकान में पूरब और पश्चिम का अजीबोगरीब संगम देखने को मिलता है।

चारसाला प्रेम: बात सही भी है। ससेक्स काउंटी क्रिकेट के पूर्व कप्तान और मशहूर टेस्ट खिलाड़ी इमरान खान के लिए पश्चिमी तौर-तरीके से जिंदगी गुजारना कभी मुश्किल काम नहीं रहा। किंतु उन्होंने अपनी पूर्वी तहजीब को कभी तिलांजलि नहीं दी। उनके लंदन स्थित शानदार एक बेडरूम वाले फ्लैट की साज-सज्जा इस बात का सबूत पेश करती है। वहां पाकिस्तानी कालीनों के साथ-साथ राजसी चमक-दमकवाले यूरोपीय सोफे भी लगे हैं और दीवारों पर जहां एशियाई प्राकृतिक दृश्य टंगें हैं, वहीं उनकी महिला दोस्त एम्मा सरजेंट द्वारा नजर किये गये पश्चिमी आकार-प्रकार के तोहफे भी रखे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि एम्मा के साथ बिताये चार सालों में ही इमरान को इस बात का यकीन हो गया था कि उनके लिए शादी करना दिन-पर-दिन नामुमकिन होता जा रहा है। उसकी वजह इमरान और एम्मा का संबंध था। चूंकि एम्मा मूल रूप से कलाकार थी इसलिए उसकी इच्छा थी कि उसे ऐसा ही जीवन साथी मिले, जिसका कला की दुनिया में डंका बज रहा हो। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए एम्मा ने इमरान को अपनाने का भरसक प्रयास किया। शायद इसीलिए उसने पाकिस्तानी तहजीब को भी अपनाने की कोशिश की। उसने मन लगाकर उर्दू जबान सीखी और इस्लाम धर्म को समझने-जानने की भी कोशिश की। इमरान के साथ वह काफी दिनों तक पाकिस्तान में रही भी, किंतु पाकिस्तान में रहकर जब उसे यह अनुभव हुआ कि अतिउदारवादी दृष्टिकोण रखनेवाली पश्चिमी महिला का इस्लामी कट्टरता में घुल-मिल पाना संभव नहीं, तो उसने इरादा बदल दिया। नतीजतन चार साल तक चले इमरान-एम्मा के प्रेम संबंधों का अंत हो गया और इमरान न चाहते हुए भी कुंआरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गये। उल्लेखनीय है कि उन दिनों क्रिकेट की दुनिया में

इमरान का ऐसा सिक्का जम चुका था कि देश-विदेश में अनगिनत खूबसूरत लड़कियां इमरान से दोस्ती करने की इच्छुक रहती थीं। किंतु इमरान को ऐसी लड़की की तलाश थी जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी तहजीब में अपने आपको घुला-मिला सके।

दूसरा मौका : इमरान खान अपनी जिंदगी के सफर में कदम-कदम पर ऐसी लड़की को तलाशते रहे जो उनकी इस कसौटी पर खरी उतर सके, ताकि उसे वे अपने बीवी बना सकें। तकदीर ने शायद उनका एक बार फिर साथ दिया। इस बार इमरान मशहूर पाकिस्तानी सर्जन (शल्य चिकित्सक) होमा खान के करीब आये। इमरान और होमा खान की जोड़ी देखनेवालों ने मन-ही-मन स्वीकार कर ली और यह उम्मीद बांध बैठे कि चूंकि इमरान को मनमाफिक लड़की मिल गयी है, इसलिए अब वे अपनी कुंआरी जिंदगी से निजात पा लेंगे। जिन लोगों ने इमरान और होमा को साथ देखा है, वे आज भी इस बात को दोहराते नहीं सकुचाते कि २८ वर्षीय होमा सचमुच इमरान के लिए अच्छी हमसफर साबित होती। दोनों की रुचियां लगभग एक-सी थीं, क्योंकि दोनों ही इस्लामी कद्रों की काफी कद्र करते थे। इमरान की तरह होमा भी सिगरेट-पान की शौकीन नहीं थी और न ही वह किसी किस्म का नशा करती थी। फिर दोनों ही पश्चिमी तहजीब में भी अपने को खपा पाने की सलाहियत रखते थे। इस्लामी मूल्यों की कद्र करनेवाली होमा भी इतने खुले दिमाग की तो थी ही कि मर्दों के बीच आजादी के अहसास के साथ काम करना उसके लिए मुश्किल बात नहीं थी। किंतु किसी को क्या मालूम था कि तकदीर इमरान का साथ नहीं दे रही थी, बल्कि उनका मजाक उड़ा रही थी। हजार समानता होने के बावजूद इमरान और होमा का प्यार शादी में सिर्फ इसलिए नहीं ढल पाया, क्योंकि इमरान लाहौर (पाकिस्तान) में रहना चाहते थे, जबकि होमा की जिद थी कि चूंकि वह नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत है, इसलिए लंदन नहीं छोड़ेगी।

शादी में जिच : होमा खान से दूरी हो जाने के बाद भी इमरान निराश नही हुए। वे इस बात पर उम्मीद बांधे रहे कि एक-न-एक दिन उनके परिवार के लोग उनके लिए मनपसंद बीवी तलाश लेंगे। लेकिन इत्तफाक से इमरान के लिए मनमाफिक लड़की नहीं मिली। कहीं रूप रंग आड़े आता, तो कहीं उम्र आड़े आ जाती। फिर इमरान को अपनी उम्र का ऐसा हौआ हो गया है कि वे अपने आपको अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी करने को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। नतीजतन उन्होंने शादी के लिए सोचना भी बंद कर दिया है और यह मान बैठे हैं कि वे अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच गये हैं, जहां उन्हें उनकी मनपसंद बीवी मिलना असंभव है। शादी के बारे में अपने बदलते नजरिये का जिक्र करते हुए इमरान कहते हैं, "मुझे तो शादी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। मैं कह नहीं सकता कि इस उम्र में पहुंच जाने के बाद मैं अब किससे शादी करूंगा। जब मैंने जवानी में कदम रखा था, तो मुझे शादी इतनी बड़ी मुसीबत नहीं लगती थी। ईमानदारी की बात तो यह है कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी शादी होगी।"

नाउम्मीदी का दौर: लंदन के अपने फ्लैट में तनहा इमरान खान

हालांकि इमरान ने इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में खेलना छोड़ दिया है, किंतु उनकी आज भी ख्वाहिश यही है कि वे गर्मियों में लंदन में रहें। यही नहीं, उन्होंने अपनी 'प्ले ब्वाय' (रसिया) जैसी छवि का भी अंत करने का फैसला कर लिया है। उनका मानना है कि अपने फन और शोहरत के बलबूते अपने आपको अमीर घराने की औलाद साबित करने के लिए फिजूलखर्ची करके अपने में मस्त रहने का स्वांग रचना ठीक नहीं है। इस संबंध में वे कहते हैं, "अपने आप में मस्त रहने या 'प्ले ब्वाय' की छवि बनाने के लिए अथाह दौलत की जरूरत होती है। कोई खुद कमाकर फिजूलखर्ची नहीं कर सकता। मैं रातें क्लबों में गुजारनेवाला व्यक्ति नहीं। सच तो यह है कि मुझे डिस्को आदि से सख्त नफरत है। अगर मैं ट्रैंप (लंदन का क्लब) में जाता हूं, तो इसलिए नहीं कि मुझे रात गुजारनी होती है, बल्कि इसलिए जाता हूं, क्योंकि मुझे अच्छे खाने का शौक है जो ट्रैंप में मिल जाता है। फिर कभी-कभी जाननेवालों से मुलाकात भी हो जाती है।"

स्वाद का चस्का : इमरान को देशी-विदेशी व्यंजनों का भी बेहद शौक है। जब वे लंदन में रहते हैं, तो मनपसंद भोजन के लिए काफी परेशान रहते हैं तथा उसकी तलाश में नित नयी जगहों पर भोजन करने जाते हैं। उनके लंदन स्थित फ्लैट में रखा फ्रिज ज्यादातर खाली ही रहता है। वह तो जब पाकिस्तान से कोई उनसे मिलने लंदन जाता है तथा उसके साथ कोई पकानेवाला होता है, तो इमरान अपना मनपसंद खाना बनवाकर अपना फ्रिज भर लेते हैं। अपने इस शौक के बारे में जानकारी देते हुए इमरान बताते हैं, "वैसे मुझे जापानी व्यंजन बहुत पसंद हैं। लंदन में भी अच्छा भोजन मिल जाता है, इतना जरूर है कि थोड़ा ढूंढ़ना पड़ता है। मुझे अंग्रेजी खाना भी पसंद है। अगर आप मुझसे यह पूछें कि दुनिया में सबसे अच्छा खाना कहां मिलता है, तो मैं कहूंगा लाहौर के फुटपाथों पर।"

कुछ भी हो, इमरान पर इस्लामी मूल्यों का ऐसा प्रभाव है कि पश्चिमी चकाचौंध से प्रभावित होने के बाद भी वे पूरी तरह से मुस्लिम समाज के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में उन्हें एक फिल्म में काम करने का भी मौका मिला, किंतु इस्लामी उसूलों की कद्र करते हुए उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। यही नहीं, उन्हें माडल बनना भी ज्यादा नहीं भाता।

फिलहाल इमरान ने अपने आपको समाज सेवा-सहायता के कार्य में लगा लिया है। यही नहीं, वे यूनीसेफ के खेल संभाग के विशेष प्रतिनिधि की हैसियत से काम करने को भी राजी हो गये हैं तथा चिकित्सकीय सहायता हेतु 'फ्रेंड्स आफ द अर्थ' संगठन की सहायतार्थ उन्होंने धन उगाहना भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, वे पाकिस्तान में जगह-जगह पर क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं। इस तरह से कुंआरे रहकर भी वे अपनी जिंदगी बेमकसद नहीं जीना चाहते। शायद दूसरों के काम आना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है।

—पियोना वाइटन

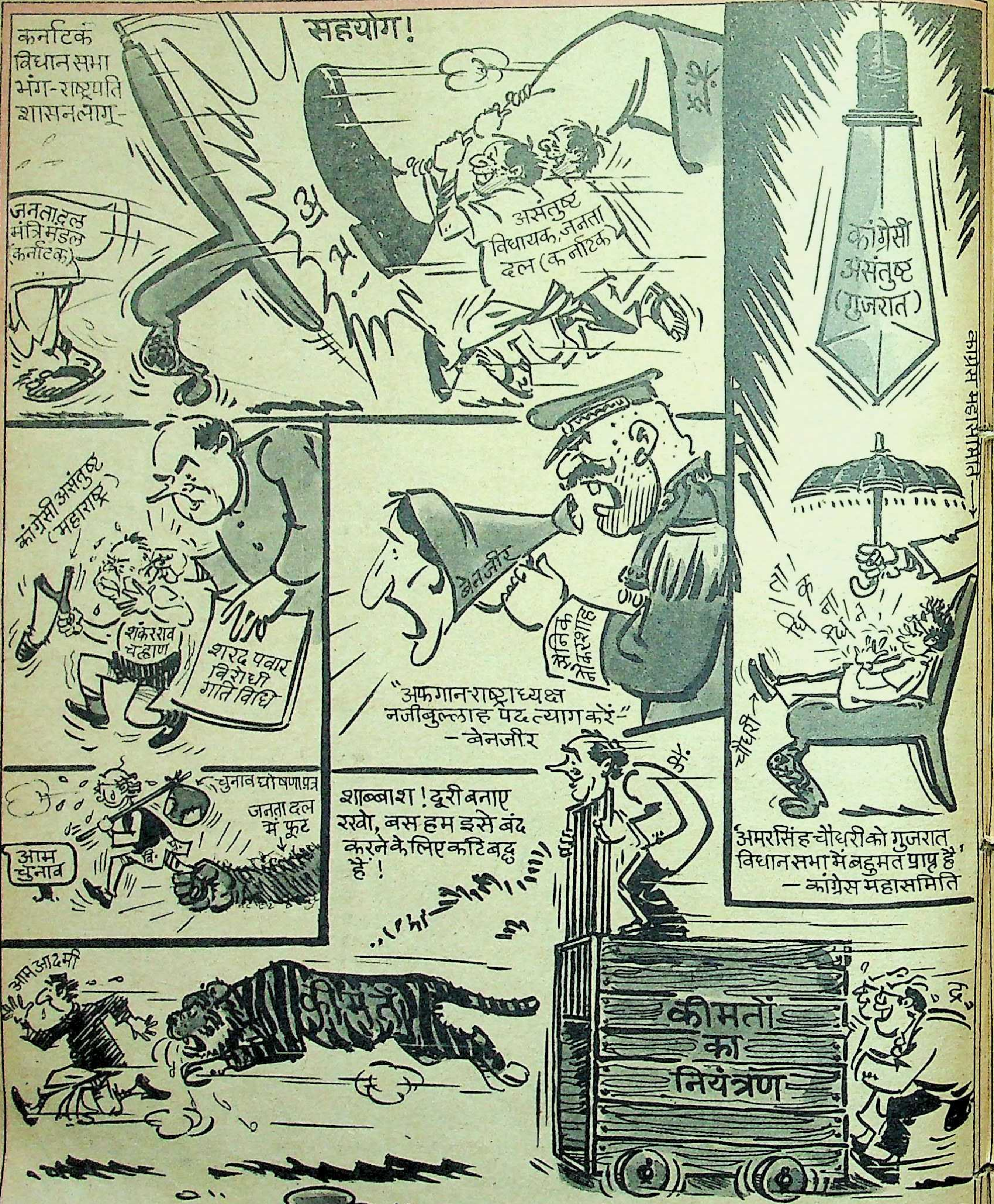
सहयोग!
कर्नाटक विधानसभा भंग-राष्ट्रपति शासन लागू-
जनता दल मंत्रिमंडल (कर्नाटक)
असंतुष्ट विधायक, जनता दल (कर्नाटक)
कांग्रेसी असंतुष्ट (गुजरात)
कांग्रेस महासमिति
ता ली क ना व ने
चौधरी
कांग्रेसी असंतुष्ट (महाराष्ट्र)
शंकरराव चव्हाण
शरद पवार विरोधी गतिविधि
बेनजीर
सैनिक नौकरशाह
चुनाव घोषणापत्र
जनता दल में फूट
आम चुनाव
वि.
शाब्बाश! दूरी बनाए रखो, बस हम इसे बंद करने के लिए कटिबद्ध हैं!
कें.
आम आदमी
कीमतें
कीमतों का नियंत्रण
द्रु.

"अफगान-राष्ट्राध्यक्ष नजीबुल्लाह पद त्याग करें" — बेनजीर

'अमरसिंह चौधरी को गुजरात विधानसभा में बहुमत प्राप्त है' — कांग्रेस महासमिति

सकती है
सौंदर्य-प्र
रहेंगे। अ
बेताब र
स्थापित
दिन दुनी
लगना अ
उद्योग है
समय-सम
सांस्कृति
होता है।
वालों की
को जानने
और मह
अलग-अ
सु
प्रयोगशा
प्रयोगशा
में निष्ण
हैं, तो क
तो महि
जाती है
रही थी
करेगी,
व्यक्तित्व
और शा
लीना च
दो आखें
तक भी
के चेहरे
झलकता
इस अद
आईना
है। अपने
का हिस्स
स
सौंदर्य अ
ऐसा इस
और गव
कोई वै
निकाला
लोगों की

सुंदरता का उद्योग

सौंदर्य आज एक बड़ा उद्योग सिद्ध हो रहा है। सुंदर होना, सुंदर बनाना दोनों की अपनी-अपनी जगह उपयोगिता है। स्त्रियों के संसार में अगर कोई नवयुवती बाकायदा गत्ते और पन्नी का मुकुट पाकर सुंदरी घोषित हो जाये, तो कहना ही क्या ? वह भारत सुंदरी से लेकर विश्वसुंदरी तक कुछ भी हो सकती है। साल भर उसके चर्चे गरम रहेंगे, उसे देश-विदेश की सौंदर्य-प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए बुलावे आते रहेंगे। अखबार, पत्र और पत्रिकाएं उसके चित्र छापने को बेताब रहेंगी और विज्ञापनदाता कंपनियां उसे माडल के रूप में स्थापित कर डालेंगी। उसकी पासबुक में जमा धन की राशि दिन दूनी रात चौगुनी होती जायेगी और वह पायेगी कि सुंदर लगना और सुंदर बने रहना उसके लिए एक अच्छा-खासा उद्योग है। परसिस खम्बाता से लेकर प्रियदर्शिनी प्रधान तक के, समय-समय पर चर्चे सुनकर यही लगता है कि किसी भी सांस्कृतिक, साहित्यिक पुरस्कार से बढ़कर सौंदर्य-पुरस्कार होता है। आज महादेवी वर्मा और महाश्वेता देवी को जानने वालों की संख्या कम और मीनाक्षी शेषाद्रि और जूही चावला को जाननेवालों की सख्या ज्यादा है। इस तथ्य में महादेवी वर्मा और महाश्वेता देवी की कोई अवमानना नहीं है। दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं।

सुंदर होना प्रकृति की देन है, तो सुंदर लगना प्रयोगशाला की। हर शहर में जगह-जगह खुलते ब्यूटी पार्लर वे प्रयोगशालाएं हैं, जहां सौंदर्य को समसामयिक बनाने की कला में निष्णात हाथ कार्य करते हैं। कहीं ये अनुभव से तपे-पके हाथ हैं, तो कहीं एकदम कच्चे। आस-पड़ोस में कोई ब्यूटी पार्लर हो, तो महिलाओं की सजधज की समस्या काफी हद तक हल हो जाती है। मेरी परिचित एक सुंदर महिला अफसर मकान ढूंढ़ रही थी। जब मैंने पूछा वह शहर के किस हिस्से में रहना पसंद करेगी, तो उसने कहा, "अपनी हेयर ड्रेसर के आस-पास।" व्यक्तित्व के प्रति यह इंद्रिय-बोध स्त्रियों की अनूठी संपदा है और शायद इसी के रहते आकर्षण का सौंदर्यशास्त्र टिका है। लीना चंद्रावरकर ने एक बार कहा था, "मैं अपनी पीठ में भी, दो आंखें रखती हूं। मैं जानती हूं कि अगर मैं उठकर टायलेट तक भी जाऊं, तो लोगों के दिल मेरे साथ-साथ जायेंगे।' लीना के चेहरे का अप्रतिम सौंदर्य जिन्हें याद हो, वे इस वक्तव्य में झलकता आत्मविश्वास भलीभांति समझ सकते हैं। जीवन को इस अदा के साथ जीना कि महसूस हो जैसे एक आदमकद आईना आपके साथ-साथ चल रहा है, स्त्री के ही बूते की बात है। अपने अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को अपनी और दूसरों की चेतना का हिस्सा बनाये रखना बड़ी बात होती है।

सुंदर होना प्रकृति की देन है, तो सुंदर लगना प्रयोगशाला की। हर शहर में जगह-जगह खुलते ब्यूटी पार्लर वे प्रयोगशालाएं हैं, जहां सौंदर्य को समसामयिक बनाने की कला में निष्णात हाथ कार्य करते हैं। कहीं ये अनुभव से तपे-पके हाथ हैं, तो कहीं एकदम कच्चे। आस-पड़ोस में कोई ब्यूटी पार्लर हो, तो महिलाओं की सजधज की समस्या काफी हद तक हल हो जाती है।

सौंदर्य अपने साथ समस्याएं भी लाता है। पुराने समय से सौंदर्य और बुद्धि का छत्तीस का रिश्ता माना गया है। शायद ऐसा इसलिए है कि रूप को हमेशा गर्व से जोड़ कर देखा गया है और गर्व ज्ञान को सीमित करता है। इस तरह की धारणा का कोई वैज्ञानिक आधार न हो, प्रचलित आधार अवश्य ढूंढ़ निकाला जाता है। मेरा विचार है कि यह धारणा जरूर उन लोगों की गढ़ी हुई होगी जिन्हें सुंदर होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। अपने अस्तित्व की महत्ता और व्यक्तित्व की प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए इस धारणा को स्थापित करना उनके लिए जरूरी रहा होगा। शायद इसीलिए आजकल वैवाहिक विज्ञापनों में इन दोनों विशेषताओं पर जानबूझ कर अलग-अलग जोर दिया जाता है। सब कहते हैं 'आवश्यकता है सुंदर, सुशील कन्या की' अथवा 'रूपवती, गुणवती वधू की।' एक अत्यंत सुंदर अभिनेत्री ने एक बार जार्ज बर्नार्ड शा से शादी का मंशा प्रकट करते हुए कहा था, "हमारे विवाह से जो संतान पैदा होगी, वह अद्भुत होगी, क्योंकि उसे मेरा रूप और आपकी बुद्धि मिलेगी।" तब बर्नार्ड शा ने प्रस्ताव के घेराव से साफ निकलते हुए कहा, "मैडम, अगर उसे मेरा रूप और आपकी बुद्धि मिल गयी, तो मामला उलटा हो जायेगा।" ताज्जुब यह है कि सुंदर स्त्रियां कभी इस बात का विरोध नहीं करतीं कि उन्हें बुद्धिमान नहीं समझा जाता और बुद्धिमान स्त्रियां इस बात का विरोध नही करतीं कि उन्हें सुंदर नही समझा जाता। जैसे दोनों ने अपनी-अपनी सीमाएं स्वीकार कर ली हैं।

कभी-कभी सौंदर्य की ललक, सनक की हद तक जा पहुंचती है। इसी सनक की जड़ में हम कास्मेटिक सर्जरी अथवा प्रसाधन-शल्य क्रिया का सबब ढूंढ़ सकते हैं। एलिजाबेथ टेलर और माइकेल जैक्सन के बारे में मशहूर है कि वे प्रायः अपने नाक-नक्श कास्मेटिक सर्जरी से संवारते रहते हैं। दोनों के व्यक्तित्व की चकाचौंध में जितना योगदान उनकी प्रतिभा और परफारमेंस का है, उतना ही उनके बाह्य स्वरूप का भी। उनके कास्मेटिक सर्जरी के किस्सों में दिनो-दिन उनके प्रशसक अपनी कल्पना के सहारे इजाफा करते जाते हैं और ये दोनों प्रतिभावान कलाकार जीते जी एक मिथक बने हुए हैं। कभी कोई पत्रिका छाप देती है कि माइकेल की नाक सिकुड़ने लगी है या उसके गाल ढहने लगे हैं, तो माइकेल-प्रशंसकों में हड़कंप मच जाता है। माइकेल जैक्सन को करोड़ों की संख्या में चिट्ठियां जाने लगती हैं, स्कूलों में बच्चे उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, उसके पोस्टरों की बिक्री दसगुनी हो जाती है और अंततः खबर को निराधार पाकर माइकेलप्रशंसक उस पत्रिका के खिलाफ जेहाद छेड़ देते हैं। स्वयं माइकेल जैक्सन ने अपनी दिलचस्प आत्मकथा 'मूनवाकर' में लिखा है, "जैसे-जैसे मैं दुबला होता गया, मेरा चेहरा बदलने लगा। प्रेस ने मुझ पर इलजाम लगाया कि मैंने शल्य-क्रिया से अपना चेहरा बदल डाला है। मैं स्वीकार करता हू कि मैंने अपनी नाक की शल्यक्रिया करवायी। फिल्मी सितारों और अभिनेताओं के लिए इस तरह की सर्जरी मामूली बात है। जूडी गार्लेंड और जीन हार्लो ने भी ऐसी सर्जरी करवायी थी। दिक्कत यह है कि लोग मेरे लड़कपन के चेहरे-मोहड़े से मेरे मौजूदा व्यक्तित्व की तुलना करते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने काफी रद्दोबदल करवायी है, जबकि सचाई यह है कि न मैंने कभी गाल और न आंखों को बदलवाने की कोशिश की। मैंने चमड़ी का रंग बदलने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया, न ही होंठों को तराशा। इस तरह के परिवर्तन हास्यास्पद होते हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता, तो मैं इन बातों को कबूल करता। मैंने सिर्फ दो बार नाक की सर्जरी करवायी है और इधर हाल में ठोढ़ी में गड्ढा डलवाया है, बस। कोई कुछ कहे, मुझे परवाह नहीं। यह मेरा चेहरा है और मैं यह बात जानता हूं।"

—ममता कालिया

अशोक कुमार

आज भी है अंदाजे-बयां कुछ और!

अविभक्तं विभक्तेषु
ज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।

धीरोदात्त व्यक्तित्व: अशोक कुमार

हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता अशोक कुमार को हाल ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अपने विलक्षण अभिनय और उदात्त व्यक्तित्व से अशोक कुमार ने जो ख्याति अर्जित की है, वह कभी इस पुरस्कार की मोहताज नहीं रही? प्रस्तुत है अशोक कुमार के फिल्मी सफर की एक अंतरंग झलक :

"दादा मुनि (अशोक कुमार) को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अब सम्मानित करने की कोई सार्थकता नहीं रह गयी है, क्योंकि उनकी पीढ़ी के लोगों को बहुत पहले इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, बल्कि उनको भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जो उनके बाद फिल्मों में आये। दादा मुनि के योगदान को नकारा नहीं जा सकता—उन्होंने फिल्म अभिनय को नयी दिशाएं दीं, फैशन-ट्रेंड और नवयुवकों के सोच को हमेशा नवीनतम अभिव्यक्ति दी। उनके जमाने का एक भी कलाकार उनके स्तर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी उनके साथ एक तरह से अन्याय ही हुआ—पहले पद्मविभूषण के बजाय पद्मश्री अलंकरण दिया गया और अब इतने विलंब से दादा साहब फाल्के पुरस्कार।" लगभग एक दर्जन से ज्यादा फिल्मकारों ने अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर उक्त आशय की टिप्पणियां कीं।

सुखद शुरुआत : १९३४ में अपने बहनोई शशधर मुखर्जी, जो उस समय बांबे टाकीज से संबद्ध थे, के पास काम की तलाश में बंबई आये अशोक कुमार ने अभिनय की शुरुआत १९३५ में की। इसके पहले कुछ दिनों तक उन्होंने बांबे टाकीज में ही तकनीशियन के रूप में काम किया था। १९३६ में उनकी तीन फिल्में ('जीवन नैया', 'अछूत कन्या' तथा 'जन्म भूमि') एक के बाद एक प्रदर्शित हुईं। इन तीनों फिल्मों की नायिका देविका रानी, निर्देशक फ्रांज आस्टिन तथा संगीतकार सरस्वती देवी (भारत की प्रथम महिला संगीतकार) थीं। यह वह समय था जब फिल्म जगत में मास्टर विट्ठल, मा० नसीर, बिलिमोरिया बंधु, गोरी, चार्ली, बरुआ, पहाड़ी सान्याल, पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, केसी डे, चंद्रमोहन, जयंत, गजानन जागीरदार, जयराज, मोतीलाल जैसे कलाकारों का वर्चस्व था। मास्टर निसार की लोकप्रियता उस समय इस हद तक थी कि लोग उनकी कार तक को पहचानते थे और जिस सड़क से वे गुजरते थे, उनकी एक झलक देखनेवालों की भीड़ जुट जाती थी। लेकिन अपनी तीन ही फिल्मों से दादा मुनि न केवल बांबे टाकीज में, बल्कि समूचे फिल्म जगत में छा गये।

देव आनंद बतलाते हैं, "एक बार दादा मुनि जब लाहौर आये, तो वहां पर सारे स्कूलों, दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी कर दी गयी थी, ताकि लोग उनका दर्शन कर सकें। मैं भी उनका दर्शन करने गया था।" दूसरी बार जब वे लाहौर 'कंगन' के प्रीमियर पर आये, तो उन्हें देखनेवालों की जो भीड़ उमड़ पड़ी थी, उनमें कामिनी कौशल भी थीं जो भीड़ को ठेलते हुए किसी तरह दादा मुनि तक पहुंच पायी थीं और उन्होंने उनके बाल खींचकर यह देखने की कोशिश की थी कि वे असली हैं या नकली। उन दिनों उनकी केशसज्जा लाखों युवा दिलों की धड़कन बन गयी थी। तब कामिनी कौशल लाहौर में स्कूल छात्रा थीं। उनके जमाने की जानी-मानी हीरोइन जद्दन बाई तो उनकी 'फैन' थीं ही, उनकी बेटी नर्गिस तथा सुरैया एक बार स्कूल से 'बंक' मार कर उन्हें नजदीक से देखने तथा आटोग्राफ लेने के लिए चुपके से बांबे टाकीज पहुंच गयी थीं। मीना कुमारी बचपन से ही उनकी इस कदर प्रशंसिका थीं कि उनकी नयी प्रदर्शित फिल्म का प्रथम शो देखने पहुंच जाया करती थीं। एक बार तो पर्स में टिकट खरीदने का भी पैसा न होने पर वे गेटकीपर की निगाह बचाकर सिनेमा हाल में घुस गयी थीं। निरूपा राय, निम्मी, मधुबाला तथा शशि कला भी बचपन से ही उनकी दीवानी थीं। बाद में ये सभी उनकी कई फिल्मों की नायिकाएं बनीं और उनके साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई। इनमें सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने मीना कुमारी के साथ कीं।

लेकिन उनके प्रति दीवानेपन की हद तो राज कपूर के विवाह के दौरान देखी गयी थी। विवाह-वेदी पर दुल्हन के रूप में लंबा घूंघट काढ़े १६ वर्षीया कृष्णा दूल्हे राज कपूर (२० वर्ष) के साथ बैठी विवाह की रस्म अदा कर रही थीं। लेकिन ज्यों ही दादा मुनि विवाह स्थल पर पहुंचे, उनके आने का हंगामा मच गया। 'अशोक कुमार आये' की आवाज कान में पड़ते ही कृष्णा कपूर ने, पृथ्वीराज कपूर का भी लिहाज न करते हुए, झट से घूंघट उठाया और दादा मुनि का दर्शन कर पुनः घूंघट पूर्ववत कर लिया।

लल्लूछाप छवि : आज की पीढ़ी यह जानने के लिए बहुत बेसब्र रहती है कि दादा मुनि १९३५-३६

के दिनों में कैसे लगते थे? एक बार इसका जिक्र चलने पर वे बोले, "उस समय मेरी छवि सचमुच लल्लू-छाप थी, लेकिन पता नहीं क्यों लड़कियां तब मेरी दीवानी थीं। अपनी एकदम पुरानी फिल्मों को देखकर आज भी मैं खूब हंसता हूं कि तब सचमुच लल्लू लगता था। अब आप ही सोचिए, चेहरे पर अच्छा-खासा मेकअप पोते, होंठों पर लिपस्टिक लगाये कोई लड़का आपके सामने खड़ा हो जाये, तो कैसा लगेगा?"

१९७२-७३ में दादा मुनि की छोटी बेटी प्रीति गांगुली जब फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में अभिनय का प्रशिक्षण ले रही थी, तब शबाना आजमी, रीता भादुड़ी, जरीना वहाब आदि अभिनेत्रियां उसकी सहपाठिनी थीं। इंस्टीट्यूट में सभी पुरानी फिल्में उन्हें दिखलायी जाती थीं। दादा मुनि की शुरुआत की फिल्में देखकर शबाना तब खुद को यह कहने से नहीं रोक पायी थीं—"ह्वाट ए चार्मिंग पर्सनाल्टी। मैं तो उन पर मरि जावां।" लेकिन अरुणा ईरानी तो कुछ कदम और बढ़ गयी थी, "अगर उन दिनों मैं जवान होती, तो दादा मुनि से जरूर विवाह कर लेती, भले ही उन्हें जबर्दस्ती 'किडनैप' (अपहृत) कर शादी के मंडप में क्यों न ले जाना पड़ता!" उस जमाने में उनके हुलिये से बंगालीपन साफ-साफ झलक रहा होता था और तब कुर्ता-धोती-पतलून उनकी प्रिय पोशाक हुआ करती थी। फिर बदलाव का दौर आया और इसके साथ-साथ उनकी पोशाक भी बदल गयी और वे कमीज-पैंट पहनने लगे। फिल्मों के जरिये एक विशेष कट की कमीज-पैंट उन्होंने बांबे टाकीज की फिल्म 'नया संसार' में सबसे पहले पहनी थी और बड़ी जल्दी वह ड्रेस युवकों का मनपसंद परिधान बन कर फैशन की चलन में आ गयी थी। 'नया संसार' में उन्होंने पहली बार सिगरेट पी थी और वह भी एक विशेष अदा में। उनकी वह अदा भी युवकों ने अपना ली थी। दादा मुनि उस समय हर काम को एक खास अंदाज और अदा के साथ करने के आदी थे।

'क्राइम डज नाट पे' विषय पर येन-केन-परिवर्तनों के साथ बननेवाली अमिताभ, जीतेंद्र, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना मार्का फिल्मों की आज बहार सी छायी हुई है, लेकिन इस विषय की शुरुआत 'किस्मत' से ही हुई थी। इसी फिल्म से 'एंटी हीरो' परंपरा की शुरुआत हुई थी और तब दादा मुनि ने अपनी इमेज को तोड़कर बड़ी खूबसूरती से चोर-नायक की भूमिका की थी। 'किस्मत' से ही 'लास्ट एंड फाउंड' कहानीवाली फिल्मों की परंपरा की भी शुरुआत हुई थी। आज बननेवाली हर तीसरी फिल्म (अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा तक की) 'लास्ट एंड फाउंड' (खोया-पाया) विषय पर आधारित होती है, जिसमें नायक किन्हीं कारणवश बचपन में मां-बाप से बिछड़ कर गलत हाथों (या लावारिस) में पड़कर बड़ा होता है और अपराधी बन जाता है।

१९४६ फिल्म इंडस्ट्री में तीन नायकों (दिलीप कुमार, देव आनंद तथा राज कपूर) के साथ एक सैलाब लेकर आया था, जिसकी रफ्तार में अधिकांश, लोकप्रिय अभिनेता अपनी पकड़ खो बैठे, लेकिन दादा मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। इसी वर्ष मधुबाला, सुरैया भी स्टारडम की शिखर पर पहुंच गयी थीं और बलराज साहनी का आगमन हुआ था।

अभिनय में नया मोड़: १९४९-५० दादा मुनि की अभिनय शैली में एक नया मोड़ लेकर आया, जब उनकी 'समाधि', 'महल', 'संग्राम' जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं। 'संग्राम' से हीरो द्वारा अपने साथ पिस्तौल रखने और उसे भिन्न-भिन्न अंदाज से चलाने की परंपरा शुरू हुई थी। उस समय वे 'बंदूकवाला' या 'पिस्तौलवाला हीरो' के रूप में अपनी इमेज बना चुके थे। फिल्म 'शक्ति' के अंतिम दृश्य में अमिताभ बच्चन एक घर में छिप कर जिस तरह से बाहर पुलिस पर गोलियां बरसाते हैं और एकाध पुलिस अफसर को अपनी गोलियों का निशाना बनाने के बाद अपनी पिस्तौल को चूमते हैं, ठीक यही सीन दादा मुनि ने 'संग्राम' में किया था। उनका यह अंदाज उस समय भी काफी लोकप्रिय हुआ था।

उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी हीरोइनें किस श्रेणी में आती हैं। अपने स्टारडम के दिनों में, जब हर बड़ी हीरोइन उनके साथ बिना किसी शर्त के काम करने के लिए तैयार रहती थीं, दादा मुनि ने शकीला ('वारंट') श्यामा ('काला आदमी'), सईदा खान ('फ्लैट नं० ९'), जयश्री गडकर ('प्रायवेट सेक्रेटरी'), बी सरोजा देवी ('हांगकांग') जैसी अनाम अभिनेत्रियों के साथ भी बड़ी खुशी से काम किया था। दिलीप कुमार से लेकर देव आनंद तथा दूसरे सितारों के साथ काम करते समय नर्गिस अपना नाम टाइटिल सीन में नायक से पहले रखने की शर्त रखती थीं, लेकिन दादा मुनि के साथ उनका नाम बाद में ही आता था। उन्होंने कभी भी उनके साथ कोई शर्त नहीं रखी थी।

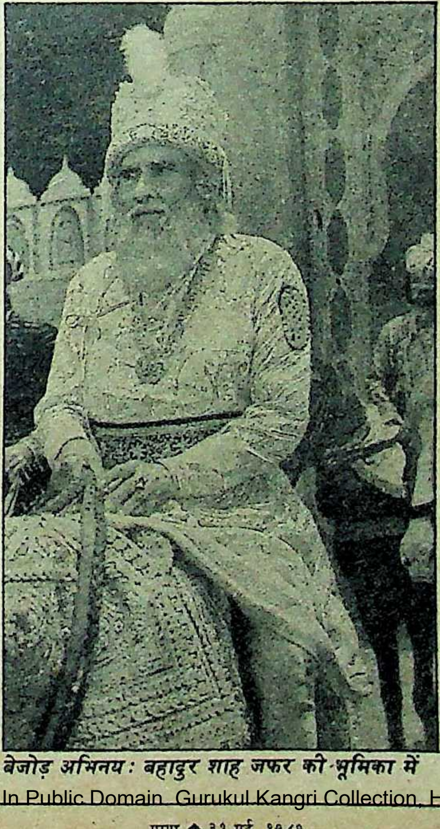
बेजोड़ अभिनय: बहादुर शाह जफर की भूमिका में

१९६१-६२ से फिल्म निर्माण का एक नया दौर शुरू हुआ, जब नायक गौण होने तथा फिल्मों में रोमांटिक लीड भर करने लगा। दादा मुनि ने इस बदलते दौर को स्वीकार किया और वे केंद्रीय भूमिकाएं करने लगे। १९६२ में 'राखी', 'आरती', 'बंदिनी', 'गुमराह', 'मेरे महबूब', 'कल और आज', 'मेरी सूरत तेरी आंखें', 'यह रास्ते हैं प्यार के' आदि प्रदर्शित हुई, जिनमें उनकी केंद्रीय भूमिका थी और रोमांटिक लीड दूसरे अभिनेताओं ने की थी। इसके अलावा उनकी केंद्रीय भूमिकावाली 'कानून', 'मेहरबान', 'गृहस्थी', 'आंचल', 'फूलों की सेज', 'आकाशदीप', 'चांद और सूरज' (बाद में 'आशीर्वाद') जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं और सराही गयीं। इस दौर में सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जीतेंद्र आदि नये कलाकारों का दौर शुरू हुआ था, लेकिन दादा मुनि यहां भी सर्वथा अप्रभावित हो अंगद के पांव की तरह जमे रहे।

चरित्र भूमिकाओं को नायकत्व का दर्जा दिलानेवाली दादा मुनि की फिल्मों का यह स्वर्ण काल था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, "किसी जमाने में मैं हिंदी फिल्मों में नायक की भूमिकाएं तो करता रहा, पर कलात्मक तृप्ति मुझे चरित्र भूमिकाओं से ही मिली।" उस समय उन्होंने 'कानून', 'गृहस्थी', 'मेहरबान', 'गुमराह', 'आशीर्वाद' इन फिल्मों की अपनी भूमिकाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया था। कहना न होगा कि उनकी फिल्म 'आशीर्वाद' राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई और इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए उन्हें भी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह यकीनन उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस दौर की उनकी उल्लेखनीय फिल्में थीं, 'विक्टोरिया नं० २०३', 'चोरी मेरा काम', 'बड़ा कबूतर', 'दो फूल' आदि।

इसके बाद जब दूरदर्शन पर सीरियलों के निर्माण की शुरुआत हुई तथा शुरू में जाने-माने कलाकार उससे कन्नी काटते रहे, तो दादा मुनि ने बिना हिचक उसे भी अंगीकार कर लिया। यहां तक कि वे 'हम लोग' के हर एपीसोड में अंत में पिछले एपीसोड तथा अगले एपीसोड की कथा बतलानेवाले सूत्रधार की एक्स्ट्रानुमा भूमिका करने से भी नहीं हिचके। इस भूमिका को भी उन्होंने खुद एक निराले अंदाज में ढाला, जिसकी नकल बाद में सभी ने की। 'दादा-दादी की कहानी', 'हम हिंदुस्तानी', 'बहादुरशाह जफर' तथा 'भीमभवानी' सीरियलों में भी काम किया और अपने अभिनय तथा अंदाज की पूरी छाप छोड़ी।

—इसाक मुजावर

देश

१६ अप्रैल : तेलुगूदेशम के विधायक आरजाजा गोपाला रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा, कांग्रेस-इ में शामिल। पंथिक समिति के सदस्य इंद्रजीत सिंह रतनगढ़ द्वारा पुलिस हिरासत में आत्महत्या।

१७ अप्रैल : देश के सवा लाख गोदी कर्मचारी वेतनवृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर। भारत द्वारा नेपाल की पारगमन संधि संबंधी पेशकश रद्द, रेवतीरमण सिंह उत्तर प्रदेश जनता दल अभियान समिति के अध्यक्ष बने।

१८ अप्रैल : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रघुनंदन स्वरूप पाठक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य निर्वाचित। झांसी के निकट कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, ५६ मृत १२५ घायल।

१९ अप्रैल : चुरहट लाटरी कांड संबंधी अर्जुन सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कैरवा बांध पर बने मकान के बारे में उल्लिखित बातों को निकालना आवश्यक नहीं। वे 'निष्कर्षात्मक तथ्य' नहीं हैं। एमपी सिंह दोबारा भारतीय हाकी टीम के कप्तान बने।

२० अप्रैल : देश के प्रथम मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' की परीक्षण-उड़ान तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्थगित।

२१ अप्रैल : भोपाल गैस दुर्घटना के दो हजार मृतकों के वारिसों को ७५० रुपए प्रतिमाह देने का उच्चतम न्यायालय का मप्र सरकार को निर्देश। कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू।

२२ अप्रैल : विदेश राज्य मंत्री केके तिवारी सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री बने। गोदी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त।

२३ अप्रैल : मणिपुर सरकार द्वारा पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के प्रतिनिधियों से बातचीत के जरिए शांति कायम करने का प्रयास।

२४ अप्रैल : राज्यसभा में जनता दल को मान्यता। कर्नाटक राज्य जनता दल के सात बागी विधायक निष्कासित।

२५ अप्रैल : लेफ्टिनेंट जनरल वीके सूद नये थलसेना उपाध्यक्ष नियुक्त।

२६ अप्रैल : हिमाचल प्रदेश मे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर कानून लागू करने का केंद्र सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री सहमत।

२७ अप्रैल : वित्तमंत्री एसबी चह्वाण द्वारा उत्पादन तथा सीमा शुल्क में १२३.२ करोड़ रुपए की राहत की घोषणा। विपक्षी दलों द्वारा बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी के विरोध में देशव्यापी विरोध दिवस का आह्वान, विरोध दिवस के दौरान उप्र में १६० गिरफ्तारं।

२८ अप्रैल : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी असम और मेघालय के राज्यपाल नियुक्त। फिल्म अभिनेता ६० वर्षीय पिंचू कपूर का निधन। जवाहर रोजगार योजना हेतु प्रधानमंत्री द्वारा २१०० करोड़ रुपए की स्वीकृति। लोकदल-ब उपाध्यक्ष कमला बहुगुणा तथा महासचिव वीपी मौर्य अपने समर्थकों सहित कांग्रेस-इ में शामिल।

२९ अप्रैल : सैमपित्रोदा दूरसंचार विभाग के सचिव नियुक्त।

३० अप्रैल : बालासोर में भयंकर तूफान, १० मरे, हजारों बेघर। फारूक अब्दुल्ला द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार ८ और मंत्री बने। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद शफी कुरैशी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नये अध्यक्ष।

हरिदेव जोशी

एसबी चह्वाण

■ *नेल्सन मंडेला*

विदेश

१६ अप्रैल : बेरूत के दंगों में स्पेन के राजदूत पेड्रो मैनुएल डी एरिस्टेग सहित २० मरे।

१७ अप्रैल : नेपाल सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के वीसा की अवधि बढ़ाने का शुल्क दुगना। ब्राजील के लुइज माटर अर्जेंटीना के मार्टिन जेय को हराकर रियो डी जेनेरो ओपेन टेनिस टूर्नामेंट विजेता बने।

१८ अप्रैल : हथियारों के विश्वप्रसिद्ध सौदागर अदनान खशोगी स्विट्जरलैंड में गिरफ्तार। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जुल्फिकार अली खान अमरीका में नये राजदूत नियुक्त।

१९ अप्रैल : ब्रिटेन की लोकप्रिय लेखिका ८२ वर्षीय डैफ्ने ड्यू मारियर का निधन। शंघाई में लोकतंत्र की मांग को लेकर हजारों छात्रों का विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन।

२० अप्रैल : अफगानिस्तान में सरकारी सेना से संघर्ष के दौरान २३ पाकिस्तानी सैनिकों सहित अनेक विद्रोही मृत। चीन के सिचुआन प्रांत में तेज ओलावृष्टि, ८७ मरे, चार हजार से अधिक घायल।

२१ अप्रैल : मुजाहिदीनों द्वारा अफगानिस्तान स्थित सोवियत दूतावास पर चीनी राकेटों से हमला।

२२ अप्रैल : दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता डा० नेल्सन मंडेला २.५ लाख डालर के पहले मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित। ईरान में १८ मादक द्रव्य तस्करों को सार्वजनिक रूप से फांसी।

२३ अप्रैल : अमरांडो काल्डरसन सोल अल सल्वाडोर के नये राष्ट्रपति बने।

२४ अप्रैल : जार्डन में मूल्य-वृद्धि के कारण हुए दंगों के चलते प्रधानमंत्री जेद-अल-रिफाई का इस्तीफा।

२५ अप्रैल : सोवियत संघ के जार्जिया गणतंत्र की राजधानी बिलिसी में लोकतंत्र समर्थक नेताओं की रिहाई के लिए तीन हजार लोगों द्वारा प्रदर्शन। सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति में भारी रद्दोबदल, निवर्तमान आंद्रेई गोमिको सहित ११० लोग समिति से बाहर। रिक्रूट कंपनी से अनधिकृत धन लेने के कारण जापान के प्रधानमंत्री नोबारू ताकेशिता द्वारा पद से इस्तीफे की घोषणा।

२६ अप्रैल : कंपूचिया की सीमा पर कालाबाजारी में लिप्त विभिन्न गुटों के बीच गोलीबारी में ३८ मरे। जापान के प्रधानमंत्री नोबारू ताकेशिता के विश्वसनीय सहयोगी इहई आओकी द्वारा आत्महत्या। विश्वप्रसिद्ध अमरीकी हास्य-अभिनेत्री लूसिले बाल का निधन।

२७ अप्रैल : जार्डन के शाह हुसैन द्वारा पूर्व सेनाप्रमुख फील्ड मार्शल जीद बिन शेकर नयी सरकार का नेतृत्व करने के लिए नामजद।

२८ अप्रैल : सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी से स्टालिन विरोधी रुख के कारण ३० वर्ष पूर्व निष्कासित इतिहासकार राय मेडवेडेव पार्टी में पुनः शामिल।

२९ अप्रैल : नामीबिया में शांति के लिए वार्ता असफल, दक्षिण अफ्रीका द्वारा सैन्य अभियान पुनः शुरू।

३० अप्रैल : श्रीलंका सरकार का शांतिवार्ता हेतु निमंत्रण जनता विमुक्ति पेरुमना द्वारा अस्वीकृत। ■

चुटकी की चुटकियां

ज़िन्दगी की [illegible]

प्यार का मस्ती भरा एहसास चुटकी पान मसाला !

चुटकी पान मसाला प्यार के रिश्तों में एक अनोखी ताज़गी और मीठी-मीठी महक लाता है। हर मौके, हर महफ़िल में रंग जमाता है। सौंफ़, छुआरा और इलायची वाला चुटकी पान मसाला कितना है निराला !

जर्दा
पान मसाला
भी उपलब्ध

Chutki
Mouth freshner
Chutki
Pan Masala with Zarda
Chutki
Chutki

वैधानिक चेतावनी: जर्दा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

“रिप्लेसमेन्ट बोंड देने का आत्मविश्वास
सिर्फ एक नाम में है–खेतान”

रिप्लेसमेन्ट बोंड कोई साधारण गारंटी या वारंटी नहीं, बल्कि खेतान सीलिंग व फ्रेशएयर पंखों के सभी खरीदारों को कम्पनी के अध्यक्ष का वादा—“मैं वचन देता हूँ कि खेतान पंखे में, यदि खरीदने के एक वर्ष तक कोई उत्पादकीय त्रुटि मिले तो उसे उसके बदले नया पंखा दूंगा।” इसका अर्थ है कि अगर ज़रा सी भी उत्पादकीय त्रुटि मिले तो मरम्मत करने की बजाय बदले में तुरंत हाथों हाथ एक नया पंखा!

यही है पूर्ण विश्वास का ठोस प्रमाण। चूंकि पंखों का उत्पादन हमारे अपने आधुनिक कारखानों में कड़े क्वालिटी नियंत्रण के अंतर्गत होता है अतः खेतान पंखे १००% खेतान हैं, जो अद्वितीय क्वालिटी के प्रतीक हैं।

उत्कृष्टता जो खेतान द्वारा उत्पादित वृहत्तम श्रृंखला के हरेक पंखे में विद्यमान है। १३५ से भी ज्यादा किस्मों के सीलिंग, टेबल, दीवाल, केबिन, पेडेस्टल, फ्रेशएयर, एग्जॉस्ट कूलर, एयर सर्कुलेटर एवं एक्सियल फ्लो पंखे कई मॉडल, साइज़ों व रंगों में उपलब्ध। वास्तव में चाहिए हवा जहाँ, खेतान है वहाँ।

खेतान—पंखों की श्रृंखला में अग्रणी, उत्कृष्टता में अद्वितीय एवं आत्मविश्वास में सर्वोपरि!

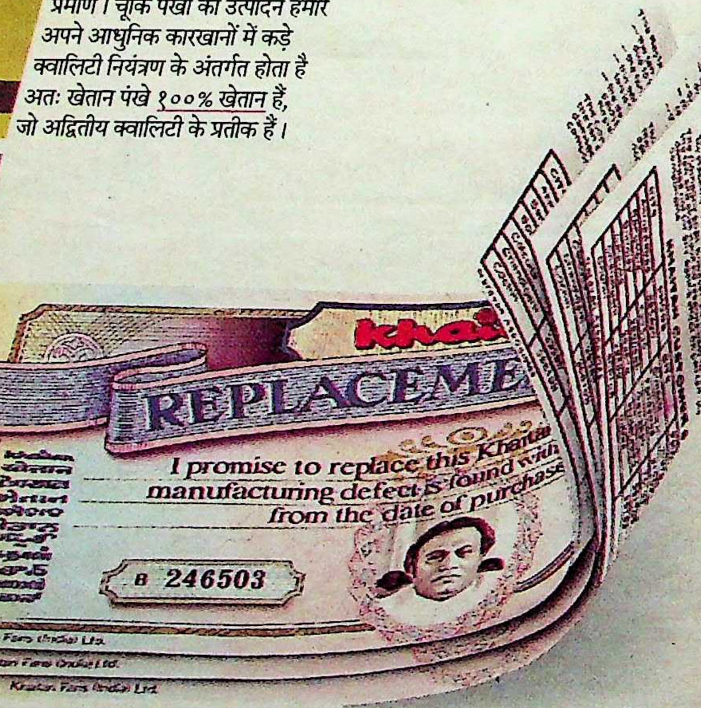
Khai
REPLACEME
I promise to replace this Khaitan
manufacturing defect is found with
from the date of purchase
B 246503
Khaitan Fans (India) Ltd.

HTA 3596A

खेतान–सिर्फ नाम ही काफी है

जब दुल्हन मंडप में जच्चा बनी !

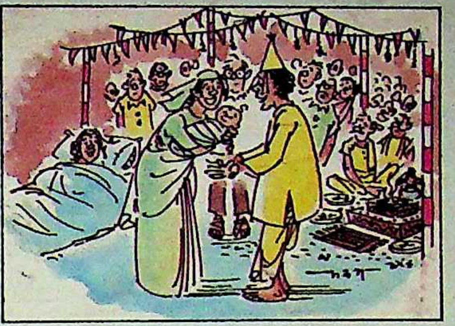

बहू पहली दफा मां बनती है, तो घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन होनेवाली बहू सात फेरों के ऐन मौके पर ही जच्चा बन जाये, तो महाभारत मचते देर नहीं लगती। हर कोई यही कहेगा कि साहब घोर कलयुग आ गया है। पिछले दिनों उड़ीसा प्रांत के गांव में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, लेकिन बात खुली, तो महाभारत नहीं हुआ।

उड़ीसा के कटक जिले के गांव जगतसिंहपुर में आयी बारात मय दूल्हे के मंडप में विवाह की रस्म पूरी करने के लिए बैठी ही थी कि उधर घरातियों के यहां एक अलग समस्या पैदा हो गयी। पंडित बड़बड़ाये जा रहा था कि जल्दी कीजिए वरना विवाह का मुहूर्त निकल जायेगा। लेकिन घराती थे कि उसकी बातों को अनसुना करते जा रहे थे। कुछ देर बाद जब शोर-गुल थमा, तो नर्स हाथ में नवजात शिशु लेकर प्रकट हुई। यह दृश्य देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पता चला कि बच्चा होनेवाली बहू ने ही जना है। लेकिन भेद खुला, तो बात बिगड़ते-बिगड़ते रह गयी। दरअसल दुल्हन और दूल्हे के बीच काफी दिनों से आंतरिक संबंध थे। नतीजतन शादी संपन्न कर दूल्हे वाले बच्ची को भी दहेज समझकर साथ-साथ लेकर खुशी-खुशी घर लौट गये।

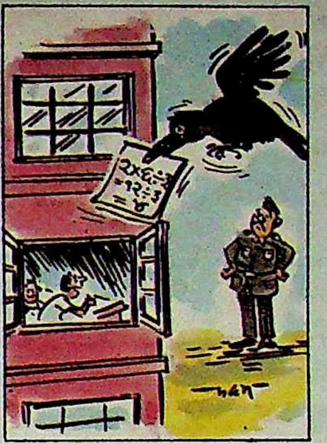

कौए की कारस्तानी

जब से स्व० राजकपूर ने फिल्म 'बाबी' बनायी और उसका गाना 'झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो' प्रचलित हुआ, तब से लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि झूठ बोलने पर कौआ काटता है, वरना कौए को तो जनम-जनम का झूठा माना जाता है। लेकिन अब तो कौआ भी धीरे-धीरे कबूतर की चाल चल रहा है। कबूतर को तो पुलिस विभाग अपनी गोपनीय खबरें पहुंचाने के लिए पालता है, लेकिन कौआ तो कौआ ठहरा, उस पर पुलिसवाले क्यों ध्यान देने लगे। पुलिस वाले ध्यान न दें, क्या हुआ, नकलचियों को तो उनसे दोस्ती से कौन रोक सकता है।

हुआ यह कि बांग्लादेश में पिछले दिनों सेकेंड्री स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों ने रिकार्डतोड़ नकल की। कोई परीक्षार्थी छुरे दिखाकर नकल करता था, तो कोई बम और पिस्तौल दिखाकर। लेकिन राजशाही सरकारी मदरसे में इम्तहान दे रहे एक परीक्षार्थी ने तो कमाल ही कर दिया। उसने एक कौए को ही ट्रेंड कर रखा था। गणित के इम्तहान के दिन परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस उप निरीक्षक ने केंद्र के ऊपर जब एक कौए को मंडराता देखा, तो उसे कुछ शक हुआ। कुछ ही देर में कौए ने एक चिट गिरायी। पुलिस उप निरीक्षक ने गिरा कागज उठाया और देखा कि उसमें तो वे ही सवाल हल किये गये हैं, जो परचे में आये हैं। वह भौंचक रह गया।

दूल्हे चार, दुल्हन एक

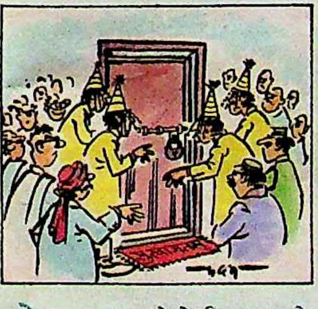

लोग रुपया कमाने के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं! कोई चोरी करता है, तो कोई डाके डालता है। कोई घूस लेता है, तो कोई नटवरलाल और नागरवाला बनता है। लेकिन कोई मां पैसा कमाने के लिए अपनी रूपसी लड़की को दांव पर लगा दे, तो विश्वास नहीं होता। लेकिन मेरठ जिले के बनत गांव की रहनेवाली वीरमती अपनी लड़की सीमा की शादी के नाम पर हजारों रुपए ठगने में सफल हो गयी।

हुआ यह कि मेरठ जिले के बनत गांव की वीरमती ने अपनी बेटी सीमा की शादी चार अलग-अलग जगहों पर एक ही दिन पक्की की और चारों दूल्हों को सरधना कस्बे के आदर्शनगर महल्ले का पता दिया। जब चारों बारातें वहां पहुंचीं, तो मकान पर ताला देखकर बिना शादी के ही चारों को बैरंग लौटना पड़ा। मेरठ जिले की मवाना तहसील के ग्राम फिटकरी से बारात लाने वालों ने बताया कि दिये पते पर जब वे लोग पहुंचे, तो वहां न तो सीमा मिली और न उसकी मां। उनका कहना था कि लड़की की मां वीरमती ने उनसे सीमा की शादी के नाम पर ३५०० रुपए की रकम ली थी। इस बारात से पूर्व मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से आयी बारात वापस ज़ा चुकी थी। उससे भी वीरमती ने ५००० रुपए शादी के लिए पेशगी ली थी। ऐसे ही एक बारात थाना परीक्षितगढ़ तथा दूसरी बारात थाना खरखौदा क्षेत्र से आयी थी। इन दोनों के ही बाराती रात तक सीमा और उसकी मां का इंतजार करते रहे, अन्ततः निराश होकर उन्हें भी लौटना पड़ा। फिलहाल वीरमती अपनी लड़की सीमा और पुत्र गुलवीर के साथ फरार है।

बंदर ने जब शराब पी

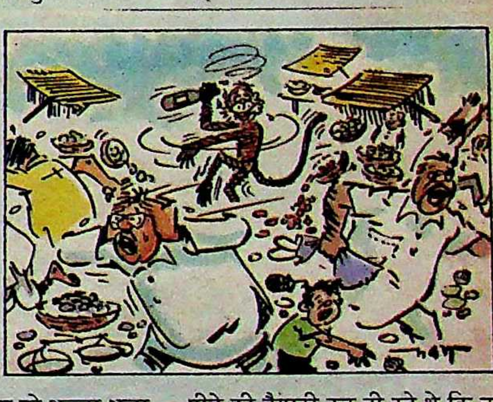

शराब पीने के बाद तो अच्छा-भला आदमी ऐसी हरकतें करने लगता है कि देखनेवालों को मजा भी आता है और कभी-कभी शामत भी आ जाती है। क्योंकि पीने के बाद जब शराब अपना रंग दिखाती है, तो पीनेवाला कहीं औंधे मुंह नाली में नजर आता है, तो कहीं किसी की मां-बहन से रिश्ता जोड़ते। यह तो आदमी का हाल है और यदि कोई बंदर दारू पी ले, तब तो पूछना ही क्या!

हुआ यों कि कुछ शराबी बरेली जिले के नवाबगंज कस्बे में सब्जी मंडी के पास बैठकर शराब पीने की तैयारी कर ही रहे थे कि न जाने कहां से एक बंदर आया और वह उनकी सीलबंद बोतल लेकर चलता बना। उन्होंने उस बंदर को काफी प्रलोभन दिया कि बोतल छोड़ दे, लेकिन बंदर कहां मानने वाला था। उसने झट बोतल की सील तोड़ी और देखते-ही-देखते एक सांस में पूरी बोतल गटक गया। नशा तो होना ही था। जब उस पर नशा चढ़ना शुरू हुआ, तो वह बेकाबू हो गया। लगा लंका-विनाश करने और जब तक नशा उतरा नहीं, तब तक जो देखा, उसे उलट-पुलट करके रख दिया।

—संयोजन : डा० मुश्ताक अली

पूनम की लहरें

पूनम ढिल्लों छाया: डीआर यादव

जब से प्रख्यात औद्योगिक संस्थान बजाज सेवाश्रम लि० ने भारत की प्रथम वीडियो फिल्म मैग्जीन का प्रायोजन अपने हाथ में लिया है, तब से पूनम ढिल्लों की रुचि 'लहरें' के प्रति गाढ़ी हो गयी है। इस संस्थान के केश तैल के लिए माडलिंग करते-करते वे सचमुच अपने बाल बढ़ाने लगी थीं और उसकी प्रशंसिकाएं पूनम जैसे केश रखने और उससे लंबे केश तथा बालों के रखरखाव का राज पूछने लगी थीं। 'लहरें' की शूटिंग के लिए पूनम ने अपने सारे पूर्व-कार्यक्रम रद्द कर दिये।

यों पूनम अपनी जिगरी सहेली पद्मिनी कोल्हापुरे के रास्ते पर चल पड़ी हैं—इस वर्ष के अंत तक वे फिल्मों से संन्यास ले लेंगी और अपने खाविंद के लिए फिल्मों का निर्माण करेंगी, ताकि वे डायरेक्टर के काम पर हाथ साफ कर सकें।

दोस्ती का अर्थ

लगभग डेढ़ दशक पहले राजेश खन्ना अपने जिन सात निर्देशकों की तारीफ करते नहीं अघाते थे, उन पर अमिताभ बच्चन (हृषिकेश मुखर्जी, जीपी सिप्पी, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, शक्ति सामंत), जीतेंद्र (जे ओमप्रकाश) और संजीव कुमार (बासु भट्टाचार्य) का जादू चल जाने के कारण वे राजेश खन्ना का चेहरा देखने से भी कतराने लगे थे। अब इन सातों निर्देशकों का सितारा धूमिल हो जाने के बाद उन्हें पुराने दोस्त राजेश खन्ना की याद आयी।

छाया: भरत चौधरी

राजेश खन्ना और बासु भट्टाचार्य

राजेश खन्ना ने बासु भट्टाचार्य की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अब वे चाहते हैं कि बासु उनके साथ मिलकर 'आविष्कार' जैसी एक और फिल्म बनायें। (राजेश खन्ना आविष्कार फिल्म को अपनी दस श्रेष्ठतम फिल्मों में से एक मानते हैं)। कहानी की समस्या नहीं है। राजेश चाहें, तो अपने बिखरे दांपत्य जीवन की कहानी ले सकते हैं और बसु चाहें, तो अपनी, क्योंकि बासु दांपत्य जीवन में तनाव तथा टूटन को लेकर फिल्में ('अनुभव,' 'आविष्कार' तथा 'गृह प्रवेश') बनाने में माहिर जो समझे जाते हैं।

एकता का इंतकाम

बड़े-बड़ों को नचानेवाले निर्माता-निर्देशकों की नाक में १६ वर्ष की एकता ने दम कर रखा है। अभी तक उसकी एक भी फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई है, लेकिन उसके पास ग्लैमरस भूमिकाओंवाली कई फिल्में हैं। एक निर्माता को तो उसके बाल करतबों से आजिज आकर बाकायदे प्रेस नोट जारी करना पड़ा। दूसरे निर्माता एस रघुनाथ तो कुछ ऐसा मुसीबतजदा हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म 'इंतकाम' से एकता को निकाल दिया। एक निर्देशक का रोना था कि जब वह 'शॉट टेक़िंग' कर रहे होते हैं, तो वह फब्तियां कसती है— 'पता नही इसे किसने डायरेक्टर बना दिया है!' और-तो-और, कैमरामैन को वह शिक्षा देती है कि 'इस एंगिल से नही, इस एंगिल से शूटिंग करो।'

लेकिन एकता इसे गलत बतलाती है और कहती है, "यह मेरे विरोधियों की चाल है, मेरी प्रगति से वे जलते हैं और अफवाहें फैलाकर मुझे फिल्मों से निकलवाने की साजिश कर रहे हैं।"

एकता छाया: विमोर

बाबरा की शर्त

बाबरा शरीफ

पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बबइया जीनत अमान का रुतबा रखनेवाली बाबरा शरीफ पिछले दिनों बंबई आयीं, तो फिल्म निर्माताओं ने उन्हें सिर पर उठा लिया। हर निर्माता के पास उनके लिए उनकी जिंदगी का 'बेस्ट रोल' था, लेकिन लखनउआ नफासत से मुस्करा कर वे कुछ इस तरह इनकार करती रहीं कि जैसे बात बन जाये, तो वे काम भी कर सकती हैं। स्व० राज कपूर उन्हें 'हिना' में लेना चाहते थे, लेकिन बात सिर्फ एक सीन पर आकर अटक गयी जिसमें उन्हें पूर्णतया दिगंबर होना था, किंतु तब पाकिस्तान की कट्टर जिया उल हक सरकार उन्हें इसकी इजाजत नहीं देती।

एक फिल्म निर्माता ने पिछले वर्ष बाबरा को दिलीप कुमार के साथ बतौर हीरोइन लेने की पेशकश की थी, लेकिन वह फिल्म भी लटक गयी, तब इसका कारण भी जिया उल हक को माना गया। पर बाबरा ने 'माया' को बतलाया, "नहीं, बात ऐसी नहीं थी। जब निर्माता ने पहली बार संपर्क किया, तो स्क्रिप्ट पूरी नहीं थी, मैं पूरी स्क्रिप्ट सुनना चाहती थी। जब वे दुबारा मिले, तो मेरा रोल स्पष्ट नहीं था। मुझे पैसे की नहीं, पावरफुल रोल की जरूरत है।"

—अखबारी लाल

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा० लि० के लिए प्रकाशित तथा
माया प्रेस प्रा० लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित।

पुस्तकालय
गु० कां० विश्वविद्यालय

उत्कृष्ट जर्मन टेक्नालॉजी

यही है वो खूबी जिसकी बदौलत, 'गैलेक्सी प्लस' दूसरे कलर टीवी से नज़र आए बिल्कुल अलग !

जर्मन परिपूर्णता का प्रतीक

मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया के जाने-माने ग्रुन्डिग (प. जर्मनी) की सहायता से निर्मित नवीनतम मॉडल गैलेक्सी प्लस में है हर वेहतरीन खूबी :

दुनिया की मशहूर जर्मन सर्किट्री. अतिआधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टी वी टेक्नालॉजी और तस्वीर एवं आवाज़ की सबसे ऊंची क्वालिटी.

गुणों की खान

गैलेक्सी प्लस में समायी हैं सबसे आधुनिक खूबियां तभी तो आप पाते हैं दृश्य और आवाज़ का ऐसा सुन्दर मेल जो अन्य किसी भी टी वी में नहीं!

प्रमुख विशिष्टताएं

- दुनिया की आधुनिक सी टी आई कलर टेक्नालॉजी.
- दुनिया के जाने-माने ७ उच्च स्तरों के ही अनुरूप.
- कई तरह के बाहरी उपकरण इस्तेमाल करने की सुविधा.
- टाइमर चिमर सहित प्री-प्रोग्राम ऑन-ऑफ़ करने की सुविधा.
- ३९ + ए वी प्रोग्राम क्षमता.
- मैमोरी सहित ९९ चैनेल.
- अधिक से अधिक वोल्टेज उतार-चढ़ाव की प्रतिरोधक शक्ति.
- बिजली की कम खपत (६० W) और ऑटो "स्विच ऑफ़" सुविधा.
- बेहतरीन आवाज़ आउटपुट (८ W)
- सम्पूर्ण कार्य संचालन रिमोट कंट्रोल द्वारा.

कोनार्क टेलीविज़न लिमिटेड की पेशकश

नये ज़माने का गैलेक्सी प्लस आपके लिए पेश करते हैं कोनार्क टेलीविज़न लिमिटेड - देश-भर में फैले अपने ५०० सी भी अधिक विक्रेताओं के ज़रिए.

नया गैलेक्सी प्लस.

अपने नज़दीकी विक्रेता के यहां आइए. और देखिए इसका कमाल... आज ही!

कोनार्क टेलीविज़न लिमिटेड
(उड़ीसा सरकार का उपक्रम)
इलेक्ट्रॉनिक्स भवन,
भुवनेश्वर ७५१ ०१०.
फ़ोन : ५३४४१. टेलेक्स : ०६७५-२७१.

जर्मन टेक्नालॉजी का करिश्मा

GALAXY PLUS 7 SYSTEM

KONARK TV

CONTOUR ADS-KTL-44/89 HIN

कुछ भी भरिये, शान से रखिये

बिन्नी के पैट कन्टेनर। बेहतरीन जार और बोतलें,
जिनमें आप मसाले, नमकीन, दाल, अचार, शरबत ...
कुछ भी रख सकते हैं।
सारा सामान ताज़ा और सुरक्षित रहे।
आपके किचन की शोभा भी बढ़े।

Binnie's
PET CONTAINERS

हल्का वज़न • दिखने में शानदार

गधरहित • न टूटने वाले

JIL Plastics : A Division of Jagatjit Industries Ltd, C-35, Sector 57, Phase III, Noida (U.P.) Tel. No. : 8922957

everest/d89/JP/90 hin R

सर्वाधिक बिकने वाली
समाचार पत्रिका
माया
वर्ष ६०, अंक ११
१५ जून, १९८९

संस्थापक
स्व० श्री क्षितीन्द्र मोहन मित्र
प्रधान संपादक
आलोक मित्र
संयुक्त संपादक
बाबू लाल शर्मा
उप संपादक
विनोद कुमार मिश्र
दिनेश दीनू
त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव (दिल्ली)
डा० मुश्ताक अली
वशिष्ठ मुनि ओझा
तारिक खान
ब्यूरो प्रमुख
बंबई: रवीन्द्र श्रीवास्तव
लखनऊ: अजय कुमार
वरिष्ठ समाचार संयोजक (दिल्ली)
रंजना कक्कड़
विशेष संवाददाता
पटना: विकास कुमार झा
संवाददाता
लखनऊ: सुरेश द्विवेदी
निशीथ जोशी
भोपाल: सुधीर सक्सेना
जयपुर: ओम सैनी
कला निदेशक
इंदु प्रकाश मुखर्जी

० प्रधान कार्यालय: २८१ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद-२११००३ फोन: ५३६८१, ५१०४२, ५५८२५, ५५७७३ टेलेक्स: ०५४०२८०, ० दिल्ली कार्यालय: ३०१/३०२ प्रकाशदीप, ७ टालस्टाय मार्ग, नयी दिल्ली-११०००१ फोन: ३३१७४१६, ३३१४७९३ टेलेक्स: ०३१, ६१७१५ लखनऊ कार्यालय: बी-१०३, गोपाला अपार्टमेन्ट्स, ५० रामतीर्थ मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-२२६००१, फोन: ३६२६२/३४४७७ पटना कार्यालय: ५७-ए, डाक बंगला-रोड, पटना-१ फोन: २६७४०, भोपाल कार्यालय: एफ-३६, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल १७ फोन: ६६३८८, बंबई कार्यालय: ८१०, एम्बेसी सेंटर, नरीमन पाइंट बंबई-४०००२१, फोन: २४३५७७, तार: माया कहानी, टेलेक्स: ११२५५७, कलकत्ता कार्यालय, स्टीफेंस कोर्ट, फ्लैट नं० ५-ए (पांचवां तल), १८ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता फोन: २९९०३५ जयपुर कार्यालय: ए-२० शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर-४ फोन: ४८१९५

Air surcharge 50 paise per copy for Dibrugarh, Dimapur, Imphal, Jorhat, Kathmandu, Mohanbari, Shillong, Silchar, Port Blair, Tinsukia and Tezepur. For Agartala, it is 25 paise.

©
इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं

३०

आवरण कथा

पंजाब के गरीब हरिजन परिवार में जन्मे और चपरासी की नौकरी से जीवन शुरु करनेवाले सरदार बूटा सिंह आज न केवल देश के गृहमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं, बल्कि प्रधानमंत्री राजीव के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार भी हैं। लेकिन इस समय वे चौतरफा हमलों की जद में हैं। इन हमलों में तेजी उस समय से और आ गयी है, जबसे उनके पुत्रों ने राजस्थान में वनस्पति उद्योग क्षेत्र में पांव रखा है। बूटा सिंह में ऐसी क्या खासियत है कि वे इंका की एक खास हस्ती बन गये हैं? क्या वे पार्टी और अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पद का दुरुपयोग कर रहे हैं?

5
75A 151184

खोजखबर
उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहे पांच रुपए के नये नोट क्या जाली हैं? १६

राजस्थान
राजस्थान में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं का उत्पादन सरकार क्यों नहीं रोक पा रही? ४७

जगन्नाथ मिश्र
प्रदेश कांग्रेस-इ अध्यक्ष बनने के बाद डा० जगन्नाथ मिश्र के सामने कौन से नये संकट पैदा हो गये? ६६

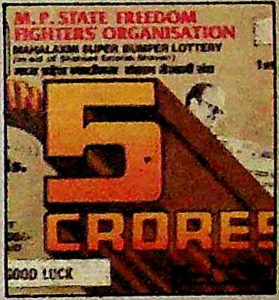
M.P. STATE FREEDOM FIGHTERS' ORGANISATION
MAHALAXMI SUPER BUMPER LOTTERY
5
CRORES
GOOD LUCK

मध्य प्रदेश
शहीद स्मारक के लिए आयोजित पांच करोड़ की इनामी राशिवाली महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी किस धोखाधड़ी का शिकार हो गयी? ६९

उड़ीसा
नंदिनी सत्पथी और जेबी पटनायक के बीच युद्ध क्यों छिड़ा है? ७५

कला फिल्में
व्यावसायिक फिल्मों की स्तरहीनता से सत्तर के दशक में उपजा कला फिल्मों का दौर इतनी जल्दी ठंडा क्यों पड़ गया? ८२

दिल्ली दरबार: पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइये १०
फोटोफीचर १३
बहस १९
भारत की छीछालेदर का
उत्तरदायी कौन? २६
महाराष्ट्र: क्या शाखर लाबी के
दिन लद गये? ४४
राजस्थान: समाज कल्याण बोर्ड:
किसका कल्याण हो रहा है? ५१
[illegible] ५७
उत्तर प्रदेश: कांग्रेस-इ बनाम जनता दल:
अध्यक्षों में द्वंद्व युद्ध ६०
प्रसंगवश: 'स्टेट्समैन' बनाम सतीश शर्मा ७९
स्त्री: टूटे सपनों की आहत आंखें ९१
दूरदर्शन: 'भारत की छाप':
एक खोजपरक यात्रा ९२
दूरदर्शन: 'बसेरा': मकान की समस्या
का फिल्मी हल ९३
व्यक्तित्व: अनीता-सिद्धार्थ: एक दूजे के लिए ९४
परदे के पीछे ९६

जीवन की उन्मुक्त
उमगों का आनन्द लीजिए

अब लीजिए क्लासिक—
पुरुषों के लिए
जांघियों की एक अति विशिष्ट श्रृंखला।
कोमल, वज़न में हल्के और
वास्तव में टिकाऊ—अर्थात् वास्तविक
विश्वास और पसन्द
की आज़ादी के प्रतीक

Dora® Classic

डोरा® क्लासिक

एक अनुपम कलात्मक प्रस्तुति

एच.पी. टेक्सटाईल मिल्स
कलकत्ता • नई दिल्ली • बम्बई • अहमदाबाद • कानपुर

Ankur/HPT/489/HIN

माया
देश पर पाकिस्तान का अघोषित हमला

देश पर पाकिस्तान का अघोषित हमला

‘माया’ के ताजा (३१ मई ’८६) अंक के प्रायः सभी लेख पठनीय—अपने-अपने विषय के जायके और जानकारियां देनेवाले—लगे। इस अंक का ‘दिल्ली दरबार’ इंका की केंद्रीय कुरूपता, राज्यपाल वेंकटसुब्बैया की केंद्रपरस्ती और जनतादल की भितरघात को जिस पैनी फंतासी के जरिये बेनकाब करता है, वह काबिलेतारीफ है और ऐसा ‘माया’ ही कर सकती है। आवरण कथा ‘देश पर पाकिस्तान का अघोषित हमला’ जितना मौजूं है, उतना ही आंख खोल देनेवाली जानकारियों तथा विचारोत्तेजक तर्कों से भरपूर। हमारा विचार है कि फारूक अब्दुल्ला को सब तरफ से सहयोग और समर्थन दिया जाना चाहिए ताकि वे कश्मीर की रक्षा कर सकें और अलगाववादी ताकतों को कुचल सकें। अरुण नेहरू अपने साक्षात्कार में काफी आक्रामक लगे, देखना है कि उनका यह रुख अगले चुनाव में कोई गुल खिलाता है या नहीं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान की मौजूदा राजनीति तथा स्थिति पर भी ‘माया’ ने अच्छी सामग्री दी है।—**डा० हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, डा० मंजीत कुमार, काहिविवि, वाराणसी।**

इंदिरा हत्याकांड

अपने १५ मई, १६८६ के अंक की आवरण कथा ‘इंदिरा हत्याकांड: व्यापक षड्यंत्र या चुनावी हथकंडा’ में ‘माया’ ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया है। पूरी कथा पढ़ने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार का लक्ष्य इस हत्याकांड को पुनः उभारकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। किंतु सवाल यह उठता है कि क्या हमारी जनता वास्तव में इतनी मूर्ख है? नहीं, जनता अब जान चुकी है कि दो मुख्य हत्यारों को चार महीने पहले ही फांसी पर लटकाकर अब हत्यारों की खोज की जा रही है और जिस हत्याकांड का अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय से हो चुका है, उसको अब खोलकर बात बढ़ायी जा रही है। राजीव की सरकार हमेशा लोकप्रियता हासिल करने के लिए नया-नया स्वांग रचती है। परंतु क्या वह इसमें सफल होती है? देखेंगे, इसी साल राजीव के इस व्यापक षड्यंत्र को।—**मु० जावेद खान, सीए ४७, नयी कालोनी, घासीकटरा, गोरखपुर।**

१५ मई, १६८६ की ‘माया’ की आवरण कथा’ व्यापक षड्यंत्र या चुनावी हथकंडा’ पढ़ी। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी, इंदिरा हत्याकांड के लाभ को एक बार पा चुकी है, तथा उसके येन-केन प्रकारेण ऐसे प्रयास रहे हैं कि इस हत्याकांड की छाप, मतदाताओं के मानस पटल पर बनी रहे ताकि एक बार और इसके लाभ भुनाये जा सकें। इस संबंध में प्रधानमंत्री राजीव गांधी भले इसके खिलाफ रहे हों, लेकिन कुछ कांग्रेसियों के प्रयास इस ओर रहे हैं तथा ऐसे प्रयासों में वे सफल भी रहे हैं। यह पार्टी को रसातल में ले जाने का उनका स्वयं का प्रयास भी है।—**विजय कुमार पहूजा, ३२३ एम खातीवाला रैंक, इंदौर, मप्र।**

‘माया’ के १५ मई के अंक की आवरण कथा स्पष्ट करती है कि सचमुच प्रधानमंत्री, इंदिरा हत्याकांड की चर्चा पुनः प्रारंभ कर आगामी चुनाव में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देख रहे हैं। अगर श्रीमती गांधी की हत्या में व्यापक षड्यंत्र हुआ है, तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। अगर इसे आगामी चुनाव का आधार बनाया जायेगा, तो वह इंका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।—**भरत जैन, १७/१३६, शास्त्री वार्ड, सागर, मप्र।**

‘माया’ (१५ मई) में प्रकाशित ‘इंदिरा हत्याकांड व्यापक षड्यंत्र या चुनावी हथकंडा?’ एक अतिमहत्वपूर्ण लेख है। एक ओर दो अपराधियों को फांसी पर लटका दिया गया, दूसरी ओर ठक्कर आयोग द्वारा इसी कांड की जांच की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर केवल ‘इंडियन एक्सप्रेस’ द्वारा कुछ अंश प्रकाशित किये जाने के कारण आयी, अन्यथा ‘देश की सुरक्षा को खतरा’ कही जानेवाली यह रिपोर्ट जनता से छिपी रह जाती। आखिर उसी रिपोर्ट ने अब देश की सुरक्षा को क्यों प्रभावित नहीं किया? यह केवल कुछ अन्य लोगों को इस कांड में फंसाने की क्रिया है, अन्यथा एक समाप्त कांड को क्यों पुनः आरंभ किया गया?

वैसे भी भारतीय राजनीति केवल स्वार्थ की राजनीति है, चाहे पार्टी कोई भी हो, इसलिए यह और कुछ नहीं, कांग्रेस-इ का चुनावी हथकंडा है।—**एम्ब्रोज पी सिंह, मिर्जापुर, उप्र।**

न्याययुद्ध किस अन्याय के खिलाफ?

‘माया’ (१५ मई) में ‘न्याय युद्ध: किस अन्याय के खिलाफ?’ पढ़ने से ऐसा लगा कि चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय राजनीति में आने से अपने राज्य में पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हरियाणा में विपक्षी सरकार होने के कारण केंद्र ने जो पक्षपात किया है, उसका पूरा फायदा उठाने और हरियाणा में खोया हुआ जनसमर्थन फिर से प्राप्त कर अभूतपूर्व सफलता पाने के लिए देवीलाल ने न्याय युद्ध का बिगुल बजाया है।—**नारायण जेठवाणी, सिंधी कालोनी, चालीस गांव, महाराष्ट्र।**

‘माया’ का १५ मई का अंक मिला। ‘न्याय युद्ध: किस अन्याय के खिलाफ’ शीर्षक लेख से स्पष्ट होता है कि चौ० देवीलाल द्वारा छेड़ा गया न्याय युद्ध भ्रष्ट और जनविरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इस पूरे कार्यकाल में आतंकवादी, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिला। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अब आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं। अतः देश की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आवेगी। अभी जन का मुकाबला धन से होता है, पर अब होनेवाले चुनावों में जनता धन का मुकाबला जन से करेगी।—**सीआर लेगा, खेरवा डेगाना, नागौर, राजस्थान।**

यंत्र नार्यस्तु पीटंते, रमंते तत्र...

‘माया’ के मई प्रथम अंक में श्रीमती ममता कालिया का लेख ‘यत्र नार्यस्तु पीटंते, रमंते तत्र...’ पढ़ा। ऐसा प्रतीत हुआ कि सचमुच समाज के दहेज लोभी, हमारी बेटी-बहनों को दहेज की बलिदेवी पर चढ़ाकर देश को एक दिन भयावह स्थिति में ला देंगे। इसलिए दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए देश के युवा वर्ग को सामने आने की जरूरत है। सरकार के केवल कानून बनाकर पारित कर देने से दहेज की यह कुप्रथा कभी समाप्त नहीं हो सकती। दहेज को समाप्त करने के लिए देश के नारी वर्ग को भी आगे आना होगा।—**गिरीश कुमार, सुगर फैक्ट्री बाजपुर (नैनीताल), उप्र**

‘स्त्री’ स्तंभ के अंतर्गत ममता कालिया के लेख ‘यत्र नार्यस्तु पीटंते, रमंते तत्र...’ (माया १५ मई) से सहमत होते हुए भी मैं यह कहना चाहूंगी कि इस मानसिकता के पीछे खुद हमारी जाति यानी स्त्रियां भी जिम्मेदार हैं। लेन-देन पर सर्वप्रथम बात महिलाओं मे चलती है। परस्पर तुलनाएं की जाती हैं कि फलां की बहू इतना सामान लाई थी और फलां को इतना मिला। सास या ननद के ताने बहू को मौत के मुंह में धकेलते जरा भी नहीं हिचकते। मेरा यहां पुरुषों को निर्दोष साबित करने का इरादा कतई नहीं है, पर अधिकतर मामलों में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन साबित होती हैं। पुरुषों की तरफ से उठनेवाली मांग को दृढ़ता से खतम किया जा सकता है, यदि इसमें महिलाएं सहयोग करें।

अभी हाल ही, दिल्ली में एक महिला शालिनी मल्होत्रा भी बलि चढ़ी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सब एक पुलिस परिवार में हुआ। यह सरकार व पुलिस के लिए डूब मरने की बात है। ऐसे में महिला अधिकारों की बात करना कितना बेमानी है, यह कहने की जरूरत नहीं।

हमें दूसरों को दोषी साबित करने के साथ-साथ खुद भी मिलजुल कर इस राक्षस रिवाज को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि समाज को इसके शाप से मुक्ति मिल सके।—**श्रीमती सुनीता बड़वड़, बावली, रोहतक, हरियाणा**

माफिया की सल्तनत

बिहारवासियों के लिए 'माफिया' एक आम शब्द हो चुका है, जिसका जलजला कोल माफिया, जल माफिया, शिक्षा माफिया, सहकारी माफिया और न जाने कितने रूपों में कहर बरपा रहा है। सामंतवाद के इस छद्म रूप के शिकार हो रहे हैं, वे बेकसूर जो दुर्भाग्यवश अब भी 'आजादी' शब्द को कुनैन की गोली समझ रहे हैं। राजनीति के 'बॉस' लोग अपने समीकरण संतुलित रखने के लिए इस तत्व का उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका गिरेबान इतने कूड़े-कचरे से भर चुका है कि अशिक्षा के इस घोर साम्राज्य में वे स्वच्छ प्रजातांत्रिक विधि से निर्वाचित हो ही नहीं सकते और मजबूरन सत्ता की तृष्णा उन्हें हिंसा करवाने को मजबूर करती है। मगर एक बात तय है, ऐतिहासिक प्रमाण इस बात को संतुष्ट करते हैं कि यह स्थिति युगांत की पूर्वावस्था होती है। एक 'सडेन ब्रेक' घटित होता ही है, चाहे जनमत पर सत्तासीनों की पकड़ जबर्दस्ती के बल पर कितनी भी मजबूत क्यों न हो? जब तक शोषितों को धर्म, जाति, वर्ग एवं संप्रदाय के नाम पर एकजुट न होने देने में कामयाबी मिल रही है, तब तक तो उनकी चांदी है, मगर जब शोषित सत्य का दामन थाम लेंगे, तो उनके आक्रोश का लावा क्या गुल खिलाएगा, यह सोचकर वाकई इस समय देश के तमाम बुद्धिजीवियों की रूह फना हो रही है।—**जयंत चक्रवर्ती, चौक शिकारपुर, पटना सिटी**

'माया' (१५ मई) में विकास कुमार झा के लेख 'बिहार माफिया की सल्तनत' से स्पष्ट हो जाता है कि सबसे उपेक्षित राज्य बिहार में किस तरह से माफिया सरकार चलाती है और किस प्रकार बिहार में स्वच्छ प्रशासन का दावा करनेवाली किसी भी सरकार का माफिया खुद अपने पैसे से पतन करवा देती है। इसी कारण भागवत झा आजाद जैसे स्वच्छ प्रशासक को अपनी कुरसी छोड़नी पड़ी। इसी डर से नयी सत्येंद्र नारायण सिंह सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से माफिया गिरोह से कंधा मिला लिया।

हमारे कई केंद्रीय व राज्य मंत्री भी माफिया से मिले हुए हैं। इन्हीं के इशारे पर माफिया कार्य करता है। आखिर कब तक बिहार की जनता माफिया का दमन सहन करती रहेगी? सरकार खुद राजनीतिक लाभ के लिए माफिया को शह दे रही है। इससे बिहार और उसकी गरीब जनता का भट्ठा बैठ रहा है।—**राजकिशोर त्रिपाठी, उत्तर नगर, नयी दिल्ली**

'माया का १५ मई का अंक मिला। हर लेख वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देखते हुए तथ्यपरक एवं तर्कसंगत लगा। विशेष रिपोर्ट : माफिया की सल्तनत की हर लाइन ने अपने आप में घिनौनी राजनीति के कड़वे सच को समेट रखा है। जिस प्रदेश में इस अदृश्य शक्ति (शिक्षा माफिया, सहकारिता माफिया, धनबाद माफिया) के हाथ इतने शक्तिशाली हैं कि प्रधानमंत्री के चहेते मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद को गद्दी छोड़नी पड़ी, उस प्रदेश का कल्याण कैसे होगा? यह ईश्वर ही जानें। एक तरफ तो रेलगाड़ियों की छत पर चढ़कर क्षुधा के मारे लोग आतंक से त्रस्त राज्य पंजाब की तरफ जाने से नहीं हिचकते, दूसरी तरफ, प्रदेश की जनता ने ऐसे लोगों को लंबे समय से प्रतिनिधित्व का मौका दिया है जो नैतिकता-मानवता को ताक पर रखकर 'येन-केन-प्रकारेण' अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त हैं। शायद बिहार की जनता ने भी ऐसे लोगों से समझौता कर रखा है जो हर हाल में भ्रष्टाचार के साथ हैं।—**शैलेंद्र कुमार तिवारी, हुगली, पश्चिम बंगाल**

'माया' के १५ मई के अंक में 'बिहार : माफिया की सल्तनत' शीर्षक लेख पढ़ा। वैसे तो माफिया के आतंक से बिहारवासी पहले से ही पीड़ित थे। मगर इसका अहसास आम लोगों को तब हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने लगभग अपने हर भाषण में तथाकथित माफिया की खिंचाई तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की। दुर्भाग्य से आजाद की विदाई के बाद यह उबाल भी शांत पड़ गया। नये मुख्यमंत्री ने तथाकथित माफिया को यह कहकर 'क्लीन चीट' दे दी कि 'माफिया' शब्द सुंदर नहीं है, जिन लोगों को माफिया कहा जाता है वे हमारे सहकर्मी विधायक व सांसद हैं।'—**राजीव लोचन मंटू, घोसेठ, मुंगेर, बिहार**

◆ ख्यालात

राजीव गांधी झूठ बोलने के आदी हैं, और वे इस लायक कतई नहीं हैं कि औरों को नैतिकता की नसीहत दें। **—रामकृष्ण हेगड़े, दिल्ली में।**

जो लोग मेरा मुंह बंद रखने के प्रयास में लगे हैं, उन्हें बता दूं कि जीते-जी मेरा मुंह बंद नहीं होगा...मैं सभी राजनीतिक बहुरुपियों के नकाब उतार दूंगा।**—अर्जुन सिंह, इंदौर में।**

'पंचायती राज' की बातें राजीवजी का चुनावी शिगूफा है, वास्तव में वे इसका (पंचायती राज का) अर्थ तक नहीं जानते—समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की तरह।**—वीपी सिंह, दिल्ली में।**

जो (गैरइंका दल) राज्य सरकार नहीं चला सकते, वे देश क्या चलायेंगे?**—राजीव गांधी, दिल्ली में।**

आप मेरा दर्जा घटाना (मुझे राजनीति में लाना) क्यों चाहते हैं, बंधु?**—अभिनेता दिलीप कुमार, 'इंडिया वर्ल्डवाइड' में।**

रामकृष्ण हेगड़े

अगर राजीव गांधी के पास कोई (राजनीतिक) मूल्य है (जैसा कि मेरे पास है), तो उन्हें रोज सौ बार इस्तीफा देना चाहिए।**—रामकृष्ण हेगड़े, 'टाइम्स आफ इंडिया' में।**

अगर धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है तो देश टूटेगा, लेकिन राजीव गांधी के हाथों में देश और जल्दी टूट जायेगा।**—चंद्रशेखर, दिल्ली में।**

कांग्रेस के नेताओं में न कोई अपनी जड़ है न एकता, न ही रीढ़, वे सबके सब खुशामदी हैं।**—लालकृष्ण आडवाणी, 'संडे मिडडे' में।**

केके तिवारी

पाकिस्तान हमारे लिए जो खाई खोद रहा है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।**–फारूक अब्दुल्ला, श्रीनगर में**

नेपाल खुद को भारत से दूर रखना सिर्फ इसलिए चाहता है, क्योंकि जनतंत्र की हवा भारत की ही ओर से चलती है जिससे नेपाल के राजतंत्र को खतरा है।**—नेपाली कांग्रेस के नेता गणेशमान सिंह, 'इंडियन एक्सप्रेस' में।**

सभी तथाकथित 'प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी' भारत में खूब रन बनाते हैं, लेकिन जब वेस्टइंडीज पहुंचते हैं, तो पैविलियन में ही बैठे रह जाते हैं।**—दिलीप वेंगसरकर, 'स्पोर्ट्स-वर्ल्ड' में।**

मैं शरद पवार और राजीव गांधी को चुनौती देता हूं कि वे मेरे परिवार की सारी संपत्ति अपने परिवार की संपत्ति से बदल लें ताकि पता चल जाये, किसने भ्रष्टाचार से धन बटोरा है।**—बाल ठाकरे, 'नवभारत टाइम्स' में।**

मोरचा सरकार के सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी को भ्रष्टाचार के लिए जेल भेजा जायेगा।**—राम जेठमलानी, बंबई में।**

वीपी सिंह भारतीय राजनीति के पामेला बोर्डेस हैं।**—केके तिवारी, 'संडे आब्जर्वर में।**

अंदेशा यह है कि (विपक्ष के हट जाने के बाद) अब सत्तारूढ़ दल नयी सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) से एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी और बोफोर्स पर तैयार रिपोर्टों में घालमेल करेगा।**—पूर्व पीएसी अध्यक्ष अमल दत्ता, दिल्ली में।**

विश्व-प्रसिद्ध श्रृंखला

विश्व-प्रसिद्ध खोजें
अनसुलझे रहस्य
विश्व-प्रसिद्ध रोमांचक कारनामे
विश्व-प्रसिद्ध युद्ध
विश्व-प्रसिद्ध 101 व्यक्तित्व
विश्व-प्रसिद्ध धर्म मत एवं सम्प्रदाय
विश्व-प्रसिद्ध खेल और खिलाड़ी
1988-89 विश्व-प्रसिद्ध रिकार्ड्स
विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक
विश्व-प्रसिद्ध विनाश-लीलाएं
विश्व-प्रसिद्ध दुर्घटनाएं
गुप्तचर संस्थाएं
विश्व-प्रसिद्ध जासूस
प्रेरक प्रसंग
विश्व-प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धतियां
विश्व-प्रसिद्ध बैंक डकैतियां
विश्व-प्रसिद्ध जासूसी कांड
हत्यारे

विश्व-प्रसिद्ध सभ्यताएं
रोमांस कथाएं
अनमोल खजाने
दुस्साहसिक खोज-यात्राएं

नये प्रकाशन

- विश्व-प्रसिद्ध भूत-प्रेत घटनाएं
- विश्व-प्रसिद्ध जन-क्रांतियां
- विश्व-प्रसिद्ध कुख्यात महिलाएं

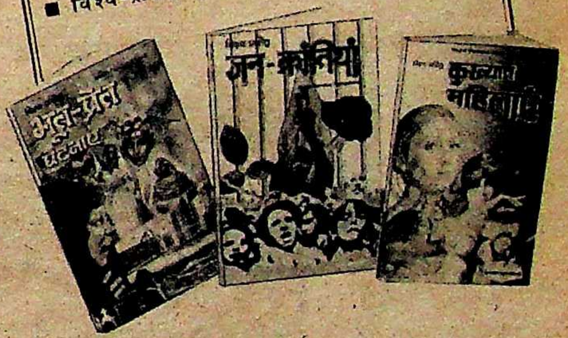
भूत-प्रेत घटनाएं
जन-क्रांतियां
कुख्यात महिलाएं

मूल्य: 18/- प्रत्येक
डाकखर्च: 4/- प्रत्येक
एक साथ चार पुस्तकें
मंगाने पर डाकखर्च माफ

■ प्रामाणिक पाठ्य-सामग्री ■ प्रत्येक पुस्तक सैकड़ों दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित ■ सरस कथा शैली ■ फोटोटाइप सैट ■ बढ़िया कागज पर ऑफसैट छपाई ■ बहुरंगी आवरण ■ वाजिब दाम

इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र से जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए उसके ज्ञान-क्षेत्र का विस्तार है। उदाहरणार्थ **रोमांचक कारनामे** में सरकंडे की नाव में की गई 13,000 मील की समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो **खोजें** में मिट्टी के तेल, पेनिसीलीन आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। ***अनसुलझे रहस्य*** में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर रक्त मिलाकर शराब पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो **खेल *और खिलाड़ी*, *101 व्यक्तित्व* व *वैज्ञानिक*** जीवनी-प्रधान पुस्तकें हैं। ***विनाश-लीलाएं*** व ***दुर्घटनाएं*** में मर्मांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है तो **गुप्तचर संस्थाएं, जासूस** व ***जासूसी कांड*** में जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं। **सभ्यताएं** और ***प्रेरक-प्रसंग*** किसी भटके हुए मन के लिए प्रकाश-स्तंभ हैं तो **हत्यारे** में रक्त पिपासु हैवानों की कथाएं हैं। ***रोमांस-कथाएं*** में लैला-मजनूं से लेकर हिटलर, कैनेडी, चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्तियों के दिलों की धड़कनें हैं तो ***अनमोल खजाने*** में रहस्य और रोमांच से भरे खज़ाने हैं। ***दुस्साहसिक खोज-यात्राएं*** में कोलंबस, मार्को पोलो जैसे खोज-यात्रियों की गौरव-गाथाएं हैं तो ***जन-क्रांतियां*** में सभी महत्त्वपूर्ण क्रांतियों का सिलसिलेवार ब्यौरा है। ***भूत-प्रेत घटनाएं*** पढ़कर आपकी रातों की नींद उड़ जायेगी—कमजोर दिल के लोग इसे न पढ़ें तो अच्छा!

*कुल मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों को उजागर करने वाला एक सचित्र **मिनि एनसाइक्लोपीडिया** है।*

इस श्रृंखला में प्रकाशित पुस्तकें:

विश्व-प्रसिद्ध.... 1. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 101 व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल और खिलाड़ी 8. रिकार्ड्स-I 9. रिकार्ड्स-II 10. वैज्ञानिक 11. विनाश-लीलाएं 12. दुर्घटनाएं 13. गुप्तचर संस्थाएं 14. जासूस 15. प्रेरक-प्रसंग 16. चिकित्सा-पद्धतियां 17. बैंक डकैतियां एवं जालसाजियां 18. जासूसी-कांड 19. क्रूर हत्यारे 20. सभ्यताएं 21. रोमांस कथाएं 22. अनमोल खजाने 23. दुस्साहसिक खोज-यात्राएं 24. भूत-प्रेत घटनाएं 25. जन-क्रांतियां 26. कुख्यात महिलाएं।

तैयारी में/प्रेस में

★ राजनैतिक हत्याएं ★ तख्ता-पलट की घटनाएं ★ मांसाहारी व अन्य विचित्र पेड़-पौधे ★ हस्तियों के प्रेम-प्रसंग

English versions available

WORLD FAMOUS... 1. Discoveries 2. Unsolved Mysteries 3. Adventures 4. Wars & Battles 5. 101 Great Lives 6. Religions, Doctrines & Sects 7. Disasters 8. Accidents 9. Civilizations 10. Scientists 11. Spies 12. Intelligence Agencies 13. Spy Scandals 14. Brutal Murderers 15. Anecdotes 16. Love-Stories of the Great People.

अपने निकट व ए. एच. व्हीलर के रेलवे व बस अड्डों के बुकस्टॉलों पर मांगें । वी. पी. पी. द्वारा मंगाने के पते :-

पुस्तक महल खारी बावली, दिल्ली-110006
शोरूम: 10-B, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.

गुंडूराव के सितारे

कर्नाटक में जनता दल के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के सितारे डूबने से पिछले तीन साल से गुम गुंडूराव के सितारे चमकने लगे हैं। कर्नाटक सरकार को गिराने के बाद अब कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश यह है कि वह विधानसभा का चुनाव जीत ले, चाहे इसके लिए अनचाहे करार दिये गये व्यक्तियों का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। कांग्रेस की इस समर नीति के तहत अब कभी भी गुंडूराव की घर वापसी हो सकती है।

एक समय संजय गांधी के चहेते और श्रीमती गांधी के 'तीसरे पुत्र' के रूप में चर्चित गुंडूराव उस समय अनचाहे हो गये थे जब १९८३ में कांग्रेस का पटरा साफ हो गया था। उस समय गुंडूराव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे बैठे थे। इसलिए वहां की हार का ठीकरा उन्हीं के मत्थे फूटा था और यह गलत भी नहीं था।

इसके बाद गुंडूराव समय की गर्द में ओझल होते गये और १९८६ में तो उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया थां। निष्कासन के बाद वे प्रणब मुखर्जी की कागजी पार्टी में शामिल हो गये थे। प्रणब मुखर्जी ने जब देखा कि वे कांग्रेस-इ से बाहर रहकर राजनीतिक रूप से जीवित नहीं रह सकते, तो वे पिछले साल कांग्रेस-इ में फिर घुस लिये, लेकिन उनके मित्र गुंडूराव न घर के रहे न घाट के। लेकिन अब समय बदला है और कांग्रेस-इ को लगने लगा है कि कर्नाटक में उसे खोयी सत्ता फिर से हासिल हो सकती है, इसलिए जो भी तिनका हाथ लग रहा है, उसी का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। फलतः गुंडूराव की भी पूछ हो गयी है।

हाजी मस्तान के खुसूसी मेहमान !

चर्चा है कि इंका के एक नामी-गिरामी महामंत्री अपनी पत्नी के साथ पिछले दिनों बम्बई पहुंचे। उन दिनों रोज़ा चल रहा था। महामंत्रीजी ने तस्कर से नेता बने हाजी मस्तान के सचिव को फोन किया कि वे अपनी पत्नी के साथ आज रोजा खोलने के वक्त हाजी साहब के घर पर शाम को आना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद इस महामंत्री को फोन गया कि वे आ सकते हैं। हाजी साहब को उनसे मिल कर बहुत खुशी होगी। ये महामंत्रीजी अपनी पत्नी के साथ हाजी मस्तान के दरबार में रोजा इफ्तार के समय पहुंच गये।

हाजी मस्तान के बम्बई स्थित महल में रोजा इफ्तार के समय में अच्छी-खासी रौनक रहती है। पूरे देश तथा अन्य देशों से मुस्लिम समुदाय के लोग उनके यहां पहुंचते हैं। रोजा खोलने के बाद इन लोगों को बहुत ही लज़ीज़ भोजन खिलाया जाता है। उसके बाद इन लोगों को उपहार दिये जाते हैं। कुछ खास लोगों को उसके बाद एक खास कक्ष में ले जाया जाता है। वहां हाजी मस्तान एक शाही कुर्सी पर होते हैं। बातचीत होने के बाद जब मेहमान विदा लेने को होते हैं, तो हाजी मस्तान ताली बजाते हैं और परदे के पीछे से एक गुलाम हाथ में काफी बड़ी थाली लेकर आता है। उस थाली के ऊपर एक सिल्क का परदा पड़ा होता है। गुलाम थाली हाजी साहब के सामने करता है। हाजी मस्तान उसे छूते हैं और उसके बाद वह थाली मेहमानों के सामने घुमायी जाती है। इस थाली में मोती, चांदी के सिक्के तथा जेवरात होते हैं। मेहमान उनमें से कुछ-न-कुछ उठा लेते हैं। जब यह थाली इन इंका महामंत्री की पत्नी के सामने आयी, तो उन्होंने उसे तीन-चौथाई खाली कर दिया। इंका महामंत्री की पत्नी अपने साथ एक काफी बड़ा थैला इसी मक़सद से लेकर वहां गयी थी।

इंका महामंत्री अपनी पत्नी के साथ जब कक्ष से विदा हो गये, तो किसी ने टिप्पणी कि 'यह क्या, यह तो सारे उपहार लेकर चली गयी।' हाजी मस्तान ने मुस्करा कर कहा, "ये लोग, बहुत भूखे हैं।"

पता चला है कि दिल्ली में आने के बाद जब यह खबर दिल्ली दरबार में पहुंची, तो वह इंका महामंत्री सफाई देने के पहले वहां पहुंच गये। उन्होंने यह बताया कि—"मैं हाजी मस्तान के यहां उसे यह समझाने गया था कि वह इस बात का भंडाफोड़ करे कि उसके यहां से जनता दल के नेता वीपी सिंह अपने इलाहाबाद चुनाव के दौरान काफी धन ले गये हैं।" इस महामंत्रीजी का दावा है कि हाजी मस्तान बहुत जल्दी वीपी सिंह पर हमला करने वाले हैं।

माथुर की नींद हराम है

हालांकि राजस्थान में असंतुष्टों के मुख्य शक्ति स्रोत हरिदेव जोशी को जयपुर से हटाकर गुवाहाटी के राजनिवास में स्थापित कर दिया गया है और असंतुष्टों के दूसरे सारथि हीरालाल देवपुरा को खुश कर लिया गया है, लेकिन फिर भी राजस्थान में मुख्यमंत्री माथुर के लिए चैन की नींद लेना संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि हरिदेव जोशी द्वारा असम के राज्यपाल की गद्दी स्वीकार कर लेने से बजाय असंतुष्ट खुश होने के नाराज हुए हैं। हरिदेव जोशी के रवैये को असंतुष्ट अपनी पीठ में छुरा भोंकने की संज्ञा दे रहे हैं।

माथुर अब यही कर सकते हैं कि असंतुष्टों को खुश करने के लिए अपने मंत्रिमंडल में जगह दें। लेकिन मंत्रिपद भी कितने लोगों को दिये जा सकते हैं। फिर असंतुष्टों को खुश करने के लिए यदि माथुर ने पद बांटे, तो अब तक वफादार रहे विधायक माथुर के खून के प्यासे हो जायेंगे। वे कहेंगे कि हमें वफादारी का क्या सिला मिला? इसलिए माथुर की कुरसी भले ही सुरक्षित रहे, उन्हें चैन की नींद नसीब नहीं होगी।

चुनाव की हवा

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा है कि चुनाव अपने समय पर होंगे। लेकिन उन्होंने इसके साथ यह भी जोड़ा है कि अन्य संभावनाएं भी खुली हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि ३१ अक्तूबर को श्रीमती गांधी की पुण्यतिथि को ऐसे ढंग से मनाया और टीवी पर दिखाया जायेगा, जिससे चुनावी लाभ मिल सके। इसके बाद चुनावों की घोषणा कर दी जायेगी। राजीव गांधी के भाषणों, उनके मंदिरों में जाने और टीवी के बदले रुख से लगने लगा है कि चुनाव-प्रचार शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के पोस्टर और बैनर विभिन्न स्थानों पर पहुंचने शुरू हो गये हैं। इस बार कार्टून पोस्टरों के जरिये विपक्ष पर हमला बोलने की योजना है।

PROTEIN-RICH
Farex-egg®
WITH CEREAL, EGGS AND MILK

अपने शिशु को प्रोटीन से भरपूर अंडे की पोषकता दीजिए

पहले से पका हुआ

फ़ैरेक्स®-एग

६ठे महीने से...

नए फ़ैरेक्स-एग में है प्रोटीन. आपके शिशु के चहुमुखी विकास के लिए जिसकी ज़रूरत है.
यह पहले से ही पका हुआ है इसलिए शिशु की कोमल पाचन शक्ति के अनुकूल है.

फ़ैरेक्स. स्वाद भी पाए, बढ़ता भी जाए... मुन्ना.

शिशु का सही विकास फ़ैरेक्स-श्रृंखला के साथ १. [illegible] फ़ैरेक्स [illegible] २. फ़ैरेक्स वेज ३. फ़ैरेक्स एग

GX/32/254 HIN

पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइये

१० मई को दिल्ली के 'खेल गांव' में इंकाइयों का 'पंचायती खेल' पूरी तरह जमाकर दिल्ली दरबार परदे के पीछे बने अपने खास कक्ष में जब आये, तो लाल बत्ती जलने के पहले ही मध्य प्रदेशीय मोती लाल वोरा मयबोरे के अंदर हो गये। जार्ज ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन आरके धवन ने जार्ज को मना कर दिया, "जार्ज, यह चुनावी साल है। मिलने-जुलने में इतनी सख्ती कतई उचित नहीं है। वोराजी को आने दो।" मणिशंकर अय्यर दरबार के सामने मल्टीनेशनल विज्ञापन कंपनी द्वारा तैयार 'पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइये, हाथ पर मोहर लगाइये' मल्टीकलर इश्तहार रखने ही वाले थे कि वोराजी बोरे से निकलकर फूट पड़े, "सर, बघेल ठाकुर (अर्जुन सिंह) न मुझे 'पंचायती हुक्का' पीने दे रहा है और न खुद पी रहा है। पूरे प्रदेश में छुट्टे सांड की तरह फुंकारे मारता हुआ घूम रहा है।" वोराजी का करुणार्द्र प्रलाप सुनकर दिल्ली दरबार की त्योरी चढ़ने लगी। धवन ने आगे बढ़कर दरबार की त्योरी खोल दी, "सर, यह चुनावी साल है। त्योरी का चढ़ना 'काउंटर प्रोडक्टिव' हो सकता है। मैं साठे को तलब करता हूं। साठे अर्जुन सिंह पर पाठा मारकर उनके मुंह में 'पंचायती हुक्का' घुसेड़ देंगे।"

खेल गांव में 'पंचायती हुक्का' गुड़गुड़ाती इधर-उधर फुदक रही सरोज खापर्डे से जब किसी ने कान में कहा कि तुम्हारे (अ) भूतपूर्व बास के आंसू नहीं थम रहे हैं, तो वे एक दर्जन रूमाल लेकर दनदनाती दरबार के खास कक्ष में घुस गयीं, "सर (वोराजी), आप से मैंने कहा था कि यहीं (स्वास्थ्य मंत्रालय) रहिए। यहां आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आपके भेजे पर तो उस समय 'आ बैल मुझे मार' सवार था।" वोराजी ने रूमालों से अपनी व्यथा पोंछते हुए सरोज के कंधे पर बिना कुछ कहे सिर रख दिया, तो मध्य प्रदेशीय इंकाई सांसद उनको कक्ष से बाहर ले जाने लगे। इतने में वसंत साठे अपनी पूरी मध्य प्रदेशीय समन्वय समिति लेकर कक्ष में आ धमके, "सर, अर्जुन सिंह बहुत तिकड़मी हैं। हम लोगों ने चुरहट लाटरी की रस्सी से उन्हें लपेट दिया था। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कसी चुरहट लाटरी की रस्सी यह कहकर खोल दी कि श्रीकृष्ण ने मुझसे कुरुक्षेत्र में कहा था, "हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है। तू मोह के बंधन से अपने को मुक्त कर।" साठे दिल्ली दरबार के सामने और सठियायें कि उसके पहले मणिशंकर अय्यर ने इशारा किया कि आप लोग कक्ष से फूट लीजिए। दरबार को 'पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइये, हाथ पर मोहर लगाइये' विज्ञापन-अभियान के इश्तहार दिखाने हैं।

वोराजी को कंधे पर लादकर जैसे ही कक्ष के

मणिशंकर अय्यर ने इशारा किया कि आप लोग कक्ष से फूट लीजिए। दरबार को 'पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइये, हाथ पर मोहर लगाइये' विज्ञापन-अभियान के इश्तहार दिखाने हैं।

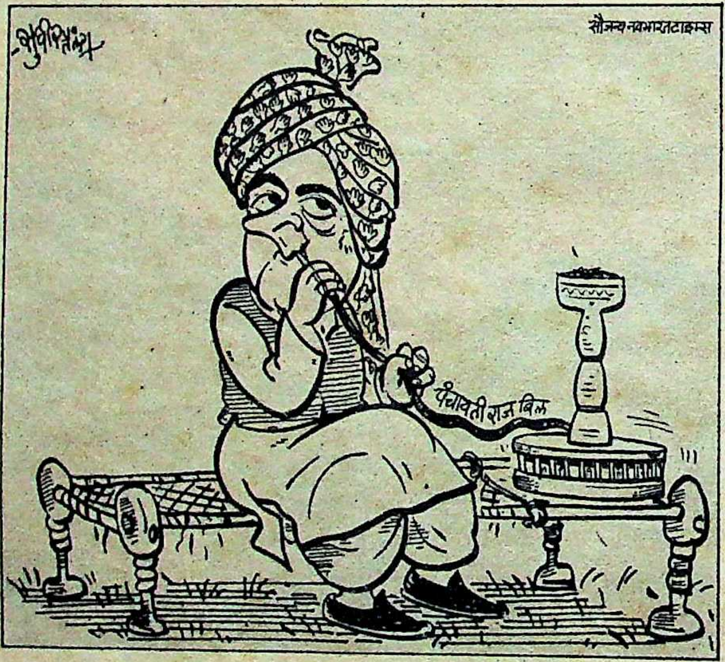

सौजन्य नवभारत टाइम्स

कक्ष में पहुंचते ही अर्जुन सिंह ने कसकर 'पंचायती हुक्का' गुड़गुड़ाया, तो दरबार का मस्तिष्क पूरी तरह झंकरित होकर पंचायती हुक्के की गुड़गुड़ाहट से अठखेलियां करने लगा।

बाहर ले जाया गया, तो सामने से पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अर्जुन सिंह आ गये। अर्जुन सिंह हल्का-सा मुस्कराये और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कक्ष के अंदर प्रवेश कर गये। अर्जुन सिंह के ओझल होते ही वोराजी बोरे से भयाक्रांत मनः स्थिति में बाहर आये, "क्या बघेल ठाकुर, दरबार के कक्ष में चला गया है!" साठेजी अपनी बत्तीसी पीसते हुए वोराजी पर बिगड़े, "वोराजी आप कह रहे थे कि अर्जुन सिंह न खुद पंचायती हुक्का पी रहे हैं और न आपको पीने दे रहे हैं। लेकिन वे तो पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दरबार में कितने आत्मविश्वास के साथ घुसे हैं।" वोराजी साठेजी को यह बतायें कि यह सब अर्जुन सिंह की नौटंकी है, उनके सामने केसरीजी (सीताराम) कमर पर हाथ रखे हुए अवतरित हो गये, "वोरा, हमने चुरहट लाटरी की आड़ लेकर अर्जुन सिंह की जगह तुमको कुरसी पर बिठा दिया। अब तुम किस मुंह से दरबार में यह शिकायत लेकर आ रहे हो कि अर्जुन सिंह अभी भी तुमको नक्कू बनाये हुए है। तुम और माधव (माधव सिंधिया) तब तो कहा करते थे कि एक बार कुरसी हाथ आ जाये, तो अर्जुन सिंह को छठी का दूध याद दिला देंगे। तुम चाहे किसी भी ओहदे पर पहुंचा दिये जाओ, रहोगे हमेशा कंसबाई संवाददाता ही। हमेशा यही न्यूज देते रहोगे कि उसकी भैंस चोरी चली गयी, उसकी गाय ने उसका खेत चर लिया।" केसरीजी के ताने के आगे वोराजी निरुत्तर ठगे से खड़े रह गये, तो पीछे से आकर एचकेएल भगतजी ने अपना 'समदर्शी दर्शन' बिखेर दिया, "संघर्ष ही जीवन है, वोराजी। हमने दिल्ली में अर्जुन सिंह से चप्पे-चप्पे पर संघर्ष किया और अंत में उसे यहां से खदेड़ कर ही दम लिया। वोराजी, अर्जुन सिंह से तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।"

कक्ष में पहुंचते ही अर्जुन सिंह ने कसकर 'पंचायती हुक्का' गुड़गुड़ाया, तो दरबार का मस्तिष्क पूरी तरह झंकरित होकर पंचायती हुक्के की गुड़गुड़ाहट से अठखेलियां करने लगा, "अर्जुन सिंहजी, आप तो मेरा पंचायती हुक्का बड़ी निष्ठा से गुड़गुड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी-अभी बताया गया कि...।" अर्जुन सिंह ने पंचायती हुक्के का एक गहरा कश लेते हुए संयत स्वर में धुआं उगलता अपना मुंह खोला, "सर, निष्ठा में आप कभी कमी न पायेंगे। आपके प्रति निष्ठा ही हमारा जीवन है। जब निष्ठा नहीं होगी, तो इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा।" अर्जुन सिंह पंचायती हुक्के का दूसरा कश लेकर अपनी निष्ठा का सार्वजनिक प्रदर्शन करें कि उसके पहले ही दरबार ने विषय बदलकर उनसे पूछ लिया, "आपके अकेले दौरे से वोराजी को यह भ्रम पैदा हो रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। आप को यह मालूम होना चाहिए कि यह जमीन न आपकी है और न वोराजी की। यह जमीन...।" अर्जुन सिंह ने अपनी ठुड्डी के मस्से को हल्का सा मुस्कराने की छूट दे दी, "सर, आपने तो अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। मैं भी अकेले घूम-घूम कर यही कह रहा हूं कि यह जमीन न वोराजी की है और न अर्जुन सिंह की। यह जमीन उन लोगों की है जो इस पर बसे हुए हैं। जो लोग जमीन पर बसे हुए हैं, वे दरबार के हैं।" दरबार ने तुरंत अपने को 'अर्जुन-दर्शन' से निकाल लिया, "वह तो ठीक है। लेकिन आप अकेले ही दौरा क्यों कर रहे हैं? इससे...।" अर्जुन सिंह ने कहा, 'श्रीमन्, हम अकेले आये थे, हमको अकेले जाना है। आपको भी अब गुरुदेव की वे पंक्तियां भाने लगी हैं—एकला चलो रे, तोमार डाक सुन जे केऊ ना आसे, तो एकला चलो रे...।" दरबार कुछ बोलें कि उसके पहले धवन ने अर्जुन सिंह के करीब आकर उनके कान में कहा, "कुंवर साहब, एकला चलो रे...की पंक्तियां जरा आहिस्ता से सुनायें। अपने पंडित नारायण दत्त तिवारी पीछे ही इंकाई पंचायत में ऋग्वेद पर सस्वर पिले हुए हैं। उनके कान में 'एकला चलो...' पड़ा नहीं कि वे यहां आकर उसका आलाप शुरू कर देंगे। आप ऐसा करें कि कल साठेजी की समन्वय समिति में बात कर लें।" अर्जुन सिंह कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन धवन ने उनको पुचकार कर कक्ष के बाहर कर दिया।

वसंत साठेजी के संसद स्थित कार्यालय में मप्र से जुड़ी हुई इंका की समन्वय समिति ११ मई को बैठी हुई थी। साठे दाना-पानी लेकर चढ़े हुए थे, "कुरसी (मुख्यमंत्री वोराजी) की अथार्टी को अगर पार्टी के अंदर से 'चैलेंज' आता है, तो लोकतंत्र तुरंत मर जाता है। अब अगर लोकतंत्र मर जाता है तो...।" शीला कौलजी को झपकी आ गयी थी, लेकिन जैसे ही उनके कान में 'लोकतंत्र के मरने' की बात गयी, वे सचेत हो उठीं, "साठेजी, मरने मारने की बात छोड़िए। चुनावी साल है, इसमें तो मिल-जुलकर किसी तरह चुनाव जीतना है। मुद्दे पर आ जायें तो...।" पास ही बैठे चंदू लाल चंद्राकर (प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष) ने शीलाजी की बात में बात मिलायी, तो मोतीलाल वोराजी के चेहरे पर फाख्ता उड़ने लगे, "अरे, यह क्या हो रहा है। अर्जुन सिंह को पानी पिलाने की जगह हर कोई उनसे मिलजुल कर काम करने की सलाह दे रहा है।" वोराजी इसके पहले अपनी 'व्यथा कथा' सुना चुके थे। उनको ऐसा यकीन था कि सारे-के-सारे लोग एक बारगी उनके समर्थन में खुलकर आ जायेंगें। उन्होंने अपने चेहरे पर उड़ रहे फाख्ता को कोशिश करके दबोच लिया, ताकि वह उड़े नहीं। अर्जुन सिंह एक घंटा बीस मिनट तक अपने मप्र के अकेले दौरे करने का पूरा दर्शन समझा चुके थे। वे कहीं से इस पकड़ में नहीं आये कि यह दौरा वोराजी या फिर दिल्ली दरबार की जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा है। लेकिन समन्वय समिति का हर सदस्य महसूस कर रहा था कि अर्जुन सिंह अपना कद वोराजी से ऊंचा करने के लिए यह दौरा कर रहे हैं।

साठेजी का जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बाहर होने लगा, तो वे चीख पड़े, "वोराजी, अब आप भी अर्जुन सिंह के साथ दौरे में जायें।" वोराजी जब तक यह कहें कि अर्जुन सिंह और मैं दोनों एक मंच पर गये, तो वे मुझे बौना बना देंगे, उसके पहले ही अर्जुन सिंह ने मोतीलाल वोरा को 'पंचायती हुक्का' थमाते हुए कहा, "पंचों का फैसला सिर माथे पर।"

मप्र से जुड़ी इंका की समन्वय समिति की बैठक में ढाई घंटे तक के तर्क-वितर्क के बाद भी जब ऊंट किसी करवट बैठता दिखायी नहीं पड़ा, तो साठेजी भड़क उठे, "कोई बीच का रास्ता निकालोगे या भस्मासुर की तरह अपने आपको ही जलाकर मार डालोगे।" अर्जुन सिंह ने उसके बाद नाक पर आ गये चश्मे को उंगली से ढकेल कर उसके ठिकाने पर पहुंचाया, "चुरहट लाटरी में फंसा अर्जुन सिंह और राजनेता अर्जुन सिंह दो अलग-अलग आदमी हैं। आप लोग दोनों अर्जुनों को एक साथ मिलाकर देख रहे हैं। मैं (अपनी सुविधा के लिए) दोनों को अलग-अलग देखता हूं।यहीं हमारे और आपके दृष्टिकोण में अंतर हो जाता है। आप मेरे चश्मे से देखें, तो सब साफ दिखेगा।" साठेजी का जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बाहर होने लगा, तो वे चीख पड़े, "वोराजी, अब आप भी अर्जुन सिंह के साथ दौरे में जायें।" वोराजी जब तक यह कहें कि अर्जुन सिंह और मैं दोनों एक मंच पर गये, तो वे मुझे बौना बना देंगे, उसके पहले ही अर्जुन सिंह ने मोतीलाल वोरा को 'पंचायती हुक्का' थमाते हुए कहा, "पंचों का फैसला सिर माथे पर।" पंचायती हुक्का अपने हाथ में लेते हुए वोराजी ने आहिस्ता से कहा, "लेकिन पनाला वहीं गिरेगा।" लेकिन इसी बीच सम्मिलित स्वर उभर आया, "पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइये, हाथ पर मोहर लगाइये।"

—दरबारी लाल

देश

१ मई : तकनीकी गड़बड़ी के कारण अग्नि का प्रक्षेपण पुनः स्थगित। इंद्रवीर चोपड़ा सूरीनाम में एवं कुंवर गजेंद्र सिंह जार्डन में भारत के राजदूत नियुक्त।

२ मई : डा० एम चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित। जम्मू-कश्मीर के खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री मंगल राम शर्मा के पुत्र रवि शर्मा द्वारा आत्महत्या।

३ मई : हरिमोहन धवन चंडीगढ़ जनता दल के अध्यक्ष एवं वीरेश प्रताप चौधरी दिल्ली जनता दल के अध्यक्ष निर्वाचित।

४ मई : हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक राम प्रताप चंदेल द्वारा इस्तीफा।

५ मई : दिल्ली में कारखाने से गैस रिसने से २०० प्रभावित, कई की हालत चिंताजनक। ८५ वर्षीय उद्योगपति नवल टाटा का कैंसर से बंबई में निधन। तमिलनाडु सरकार द्वारा १२० उम्रकैदी १४ वर्ष में ही रिहा।

६ मई : अखिल बोडो छात्र यूनियन द्वारा १६ मई से ३३० घंटे के असम बंद की धमकी। खालिस्तान कमांडो फोर्स का दूसरे नंबर का कमांडर परमजीत सिंह उर्फ पम्पा सिंह जालंधर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मृत। वित्तमंत्री एसवी चह्वाण एशियाई विकास बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष बने।

७ मई : आतंकवादियों द्वारा अकाली नेता जसमेर सिंह की फिरोजपुर में हत्या।

८ मई : रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवायी की तिथि इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा १० जुलाई निश्चित।

९ मई : संसद द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि ११ मई से ६ माह के लिए बढ़ाने का अनुमोदन। विपक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के नये अध्यक्ष पी कोलंदवेल की नियुक्ति के विरोध में अध्यक्ष बलराम जाखड़ के फैसले को चुनौती। भारतीय सुपर टैंकर कंचनजंगा सऊदी बंदरगाह के पास पुनः डूबा।

१० मई : लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ आयात की गयी चारा मशीनों के घोटाले के संबंध में लोकसभा में बहस के लिए तैयार।

११ मई : आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस-इ में शामिल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ९६ कालेजों को स्वायत्तता। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गहलोत द्वारा इस्तीफा।

१२ मई : लोकदल, जनता पार्टी और जनमोर्चा द्वारा प्रगतिशील मोर्चे का गठन। राज्यसभा सदस्य धर्मपाल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव नियुक्त। जीवी रामकृष्ण, बेल्जियम में भारत के नये राजदूत नियुक्त।

१३ मई : उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य डा० शिवानंद नौटियाल अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस-इ में शामिल। झारखंड राज्य की मांग को लेकर बिहार के सात विधायकों द्वारा विधानसभा एवं विधान परिषद से इस्तीफा।

१४ मई : विदेश मंत्री पीवी नरसिम्हाराव, विदेश सचिव एसके सिंह और केंद्रीय पर्यावरण एवं वनमंत्री जेडआर अंसारी नैरोबी के लिए रवाना।

१५ मई : पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा ६४वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश।

◆

नवल टाटा

बलराम जाखड़

विवियन रिचर्ड्स

प्रेमदास

विदेश

१ मई : पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार के तीन मंत्रियों द्वारा इस्तीफा। अर्जेंटीना के अलबर्टो मेसिनी, बोरिस बेकर को हराकर मोंटकार्लो ओपनटेनिस चैंपियनशिप विजेता बने।

२ मई : जनरल आंद्रेस रोद्रीगुएज पराग्वे के राष्ट्रपति बने।

३ मई : चीन में पत्रकारों द्वारा प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ प्रदर्शन।

४ मई : सिंगापुर में निर्धारित समय से ज्यादा रुकने पर २१ भारतीय गिरफ्तार।

५ मई : इराक के रक्षामंत्री जनरल अदनान खैर अल्लाह की हेलीकाप्टर दुर्घटना में मृत्यु। बांग्लादेश में चांदपुर शहर के एक स्टेडियम में खेल के दौरान भगदड़, २० महिलाएं मृत, ७० व्यक्ति घायल। उत्तरी चीन के श्येन चिन बंदरगाह के समीप हेलीकाप्टर दुर्घटना, १० लोग मृत।

६ मई : वेस्टइंडीज में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार के कारण वेस्टइंडीज के कप्तान विवियन रिचर्ड्स १२ महीने के लिए निलंबित तथा २५० डालर का जुर्माना। अफगान वायुसेना द्वारा जलालाबाद के आस-पास मुजाहिद्दीन ठिकानों पर भारी बमबारी, १०० विद्रोही मृत।

७ मई : पश्चिमी जर्मनी की स्टेफी ग्राफ द्वारा हैम्बर्ग महिला टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब हासिल। इस्रायली सैनिकों द्वारा कई फिलिस्तीनियों की हत्या, संघर्ष के दौरान १३५ फिलिस्तीनी घायल, साढ़े चार लाख कर्फ्यू से प्रभावित।

८ मई : स्वीडिश विमान दुर्घटनाग्रस्त, सांसदों सहित १६ आदमी मारे गये। पेरू के प्रधानमंत्री अमांडो विलानुएवा द्वारा इस्तीफा।

९ मई : वेतनवृद्धि की मांग को लेकर बीबीसी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल। हंगरी के राष्ट्रपति जानोस कादार द्वारा अस्वस्थता के कारण इस्तीफा।

१० मई : आर्मेनिया में कारखाने से जहरीली गैस रिसने से ८० व्यक्ति प्रभावित। जापान के प्रधानमंत्री नोबोरु ताकेशिता द्वारा संसद में रिक्रूट घोटाले का पूरा विवरण देने की घोषणा।

११ मई : पनामा में रह रहे अमरीकियों की रक्षा के लिए अमरीका के राष्ट्रपति बुश द्वारा ३००० सैनिक भेजने का निर्णय। चीन द्वारा नेपाल को पेट्रोल तथा नमक देने का आश्वासन।

१२ मई : जापान की सत्ताधारी लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मासायोशी द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने से इनकार। भूतपूर्व चैंपियन मुक्केबाज ३७ वर्षीय ऐस्टेबान दाजिस्स का एड्स से निधन।

१३ मई : बांग्लादेश में भीषण वर्षा, ५४ व्यक्ति मृत। श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास द्वारा शांति स्थापित करने के लिए जनता विमुक्ति पेरामुना को विचार-विमर्श हेतु आमंत्रण।

१४ मई : चीन के तीन हजार छात्रों द्वारा लोकतंत्र की मांग को लेकर भूख हड़ताल।

१५ मई : जनेज द्रनोवस्क यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति बने। गुट निरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में वेनेजुएला को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाये जाने पर पनामा द्वारा आपत्ति। कार्लोस मेनेम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने।

◆

खेल-खेल में विवाह

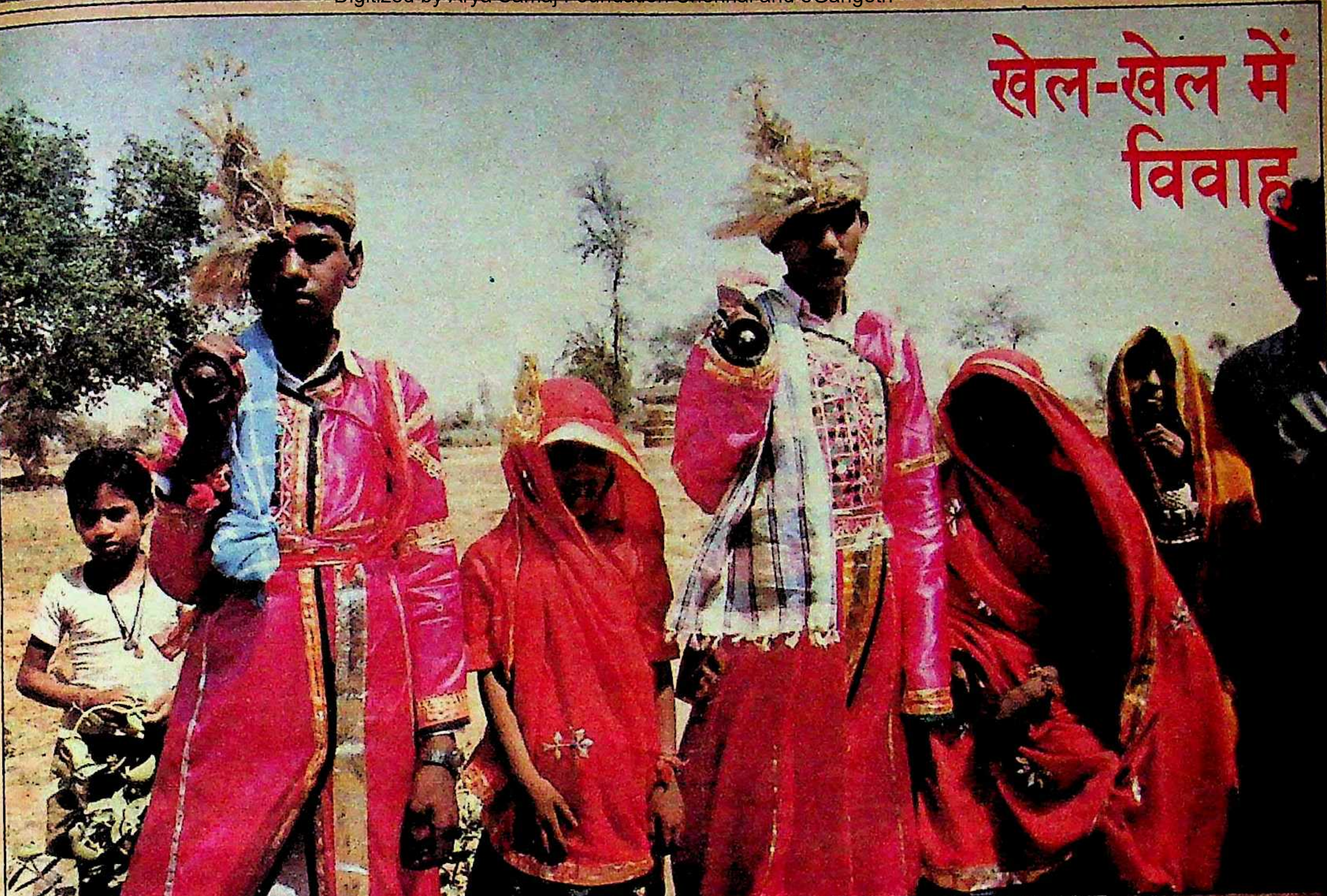

बारह वर्ष का पूरण
अपनी सात वर्षीया
पत्नी कैलाशी और
ग्यारह वर्ष का सेद्रराम
अपनी पांच वर्षीया
पत्नी मूली के साथ

भैरूं और हरिशंकर बड़े खुश हैं। हों भी क्यों नहीं, उन्हें शहर से लाये नये कपड़े और जूते पहनाये गये हैं। जैसे साफे (पगड़ी) उनके पिता और दादा बांध कर ठसक जमाते हैं, वैसे ही साफे वे भी बांधकर मगन हो रहे हैं। दोनों के हमउम्र रिश्तेदार भी इस मौके पर नये कपड़े पहनकर रामलीला का-सा आनंद ले रहे हैं। इन सबको लग रहा है, जैसे कोई स्वांग खेला जा रहा है, जिसमें गांव-ढाणी के सारे रिश्तेदार शामिल हैं। ढोल बज रहे हैं और ऐसे पकवान बन रहे हैं, जिन्हें अकसर वे हलवाई की दुकान पर ही देखते हैं और खिसा (जेब) में हाथ डालकर मन मसोस कर रह जाते हैं। आज खूब खाने को भी मिलेगा। बड़ी मौज-मस्ती रहेगी।...बस इतनी-सी समझ थी यादव जाति के दो बाल-दूल्हों और उनके साथियों की, जिन्हें विवाह के लिए जयपुर से १९ किलोमीटर दूर सांगानेर कस्बे की ग्राम वाटिका में बारात सजा कर ले जाया जा रहा था।

बालक भैरूं दूसरी कक्षा का छात्र है, यानी अभी सात साल का हुआ है। हरिशंकर, भैरूं का छोटा भाई है और पहली कक्षा में पढ़ता है। अब दुल्हनों का अंदाज लगाइये। भैरूं की दुल्हन हरिशंकर जितनी बड़ी और हरिशंकर की वधू अभी घुटनों के बल चलती है।

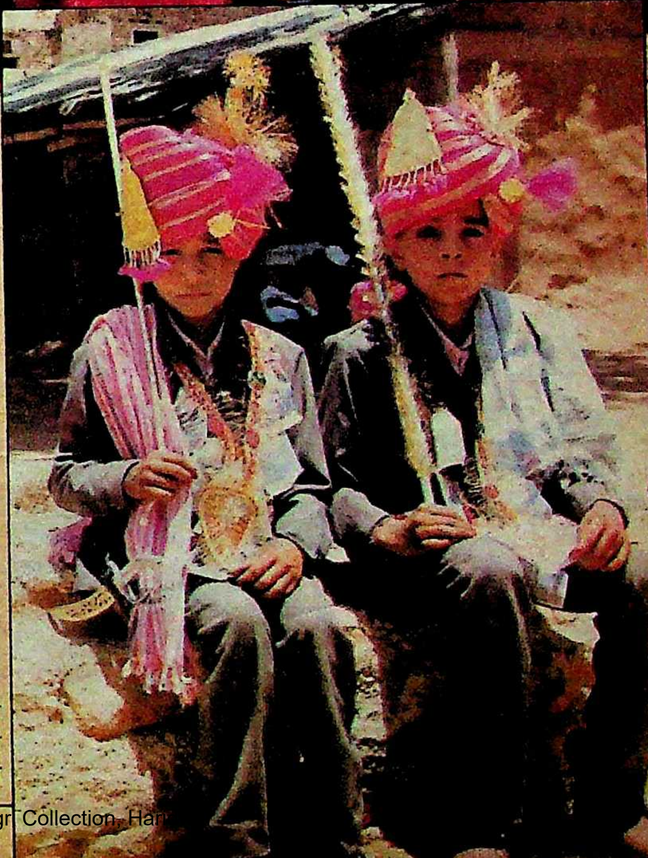

दस वर्षीय प्रभु मीणा
और आठ वर्षीय घासी
मीणा

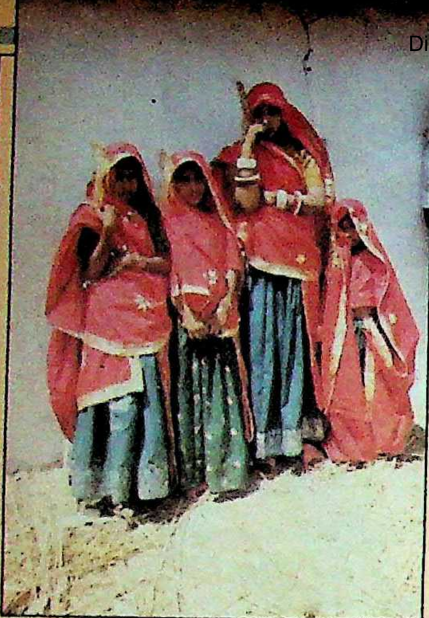

चार दुल्हनें

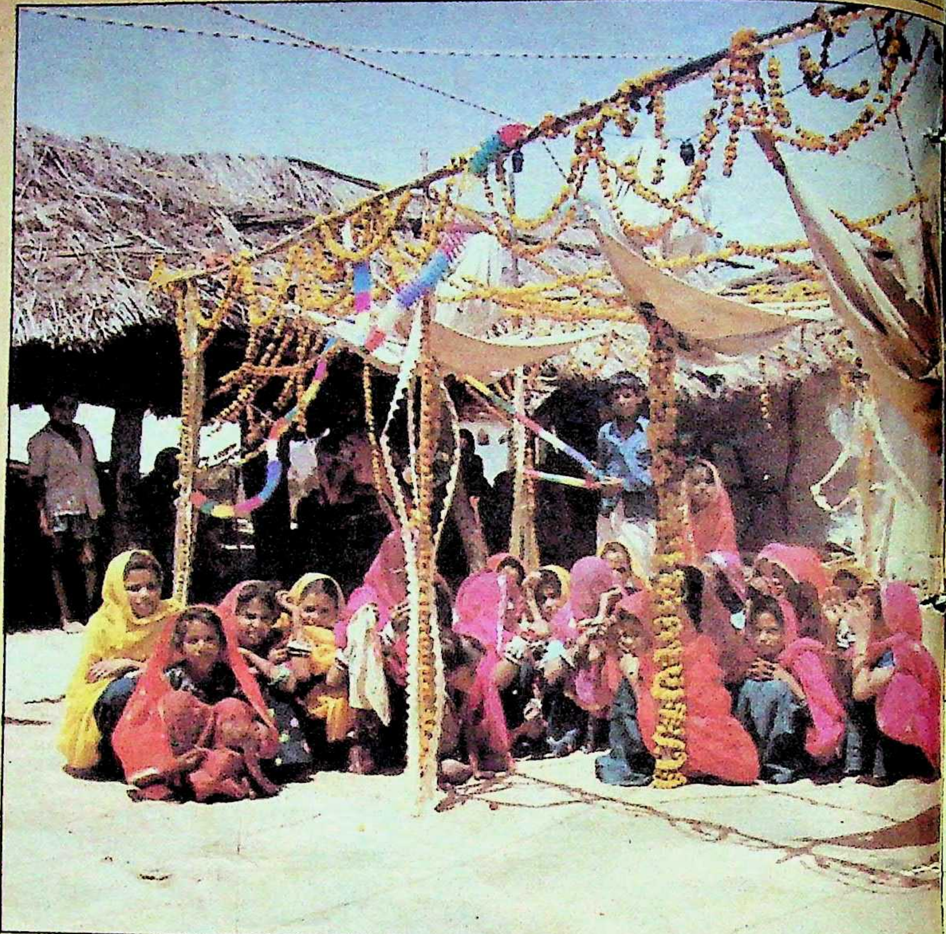

विवाह मंडप में महिलाएं

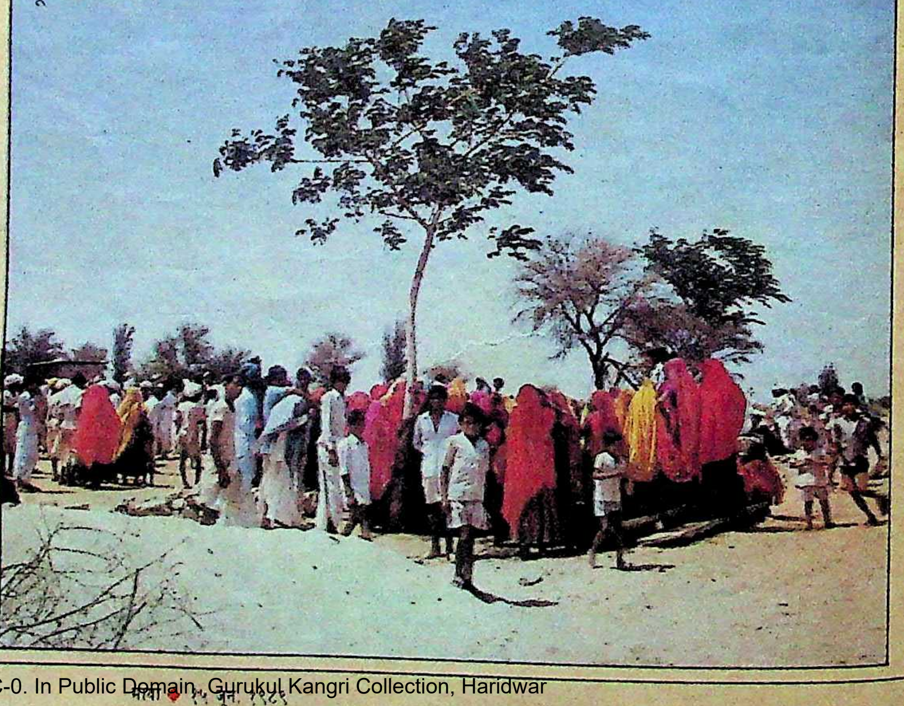

विवाह स्थल पर वर-वधू पक्ष के लोग

राजस्थान के गांवों में आखातीज (अक्षय तृतीया) के दिन ऐसे दृश्य आये वर्ष देखने को मिलते हैं। यद्यपि दूरदर्शन और अखबारों में बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार और कानूनी पाबंदी के कारण बाल-दूल्हों की बारातें इस बार खुले आम और धूमधाम से तो नहीं निकलीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। 'माया' के छायाकार को इन बालविवाहों के दृश्यों के छायांकन के लिए कोई ज्यादा खोज-खबर नहीं करनी पड़ी। 'आखातीज' के दिन उसे ऐसे दृश्य आम मिले जिन्हें इन पृष्ठों में प्रकाशित किया गया है।

राजस्थान सरकार के महिला, शिशु एवं पोषाहार विभाग ने इस बार प्रचारित किया है कि 'बाल विवाह' की कुप्रथा 'ठहर' रही है। वैसे भी कुप्रथाओं तथा यथास्थितिवाद से टकराने में राजस्थान के राजनीतिज्ञ घबराते हैं। फिर चुनाव वर्ष में यह जोखिम उठाने की क्षमता तो आज की मौकापरस्त राजनीति में बिलकुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, स्वयं राजनेता ऐसी कुप्रथाओं के शिकार रहे हैं। मसलन बिहार के वर्तमान राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य खान राज्यमंत्री नानालाल ने अपनी आठ और बारह वर्षीय पुत्रियों का बाल विवाह रचाया था। जब कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया, तो पहाड़िया का जवाब था, "कानून का उल्लंघन तो हुआ, किंतु परंपराओं की अपनी रीति होती है।" शिवचरण माथुर मंत्रिमंडल के सदस्य रामकिशन वर्मा पर भी पिछले साल आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी चौदह वर्षीय बेटी का ब्याह रचा दिया।

उल्लेखनीय है कि बाल विवाहों पर पहला एतराज राजपूताना की रियासत अजमेर के दीवान डा० हरबिलास शारदा की ओर से ही हुआ था। १५ सितंबर, १९२७ को डा० हरबिलास शारदा ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष बाल विवाह निरोधक बिल प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे अप्रैल, १९३० से लागू कर दिया। शारदा एक्ट के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु की कन्या और १८ वर्ष से

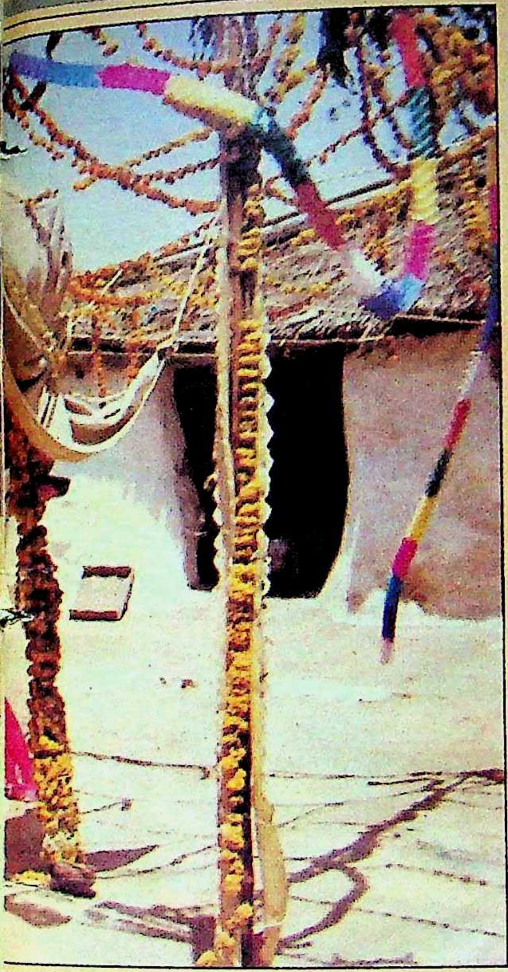

भैरूं और हरिशंकर

कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। १९४९ में इस एक्ट में संशोधन कर लड़की की आयु पंद्रह वर्ष की गयी। फिर अक्तूबर १९७८ में संशोधन हुआ, जिसमें लड़के लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमशः २१ तथा १८ तय की गयी।

उक्त कानून के बावजूद बाल-विवाह हो रहे हैं। इस कुप्रथा के चलने की वजह कानून का मुलायम होना है। उसका उल्लंघन करने पर मात्र पंद्रह दिन का सश्रम कारावास अथवा एक हजार रुपए जुर्माना होता है। पुलिस ऐसे विवाह में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक इसकी शिकायत कोई दूसरा न करे। ऐसी स्थिति में बाल विवाह की घातक परंपरा को रोक पाना असंभव है।

ऊंट गाड़ी पर बारात

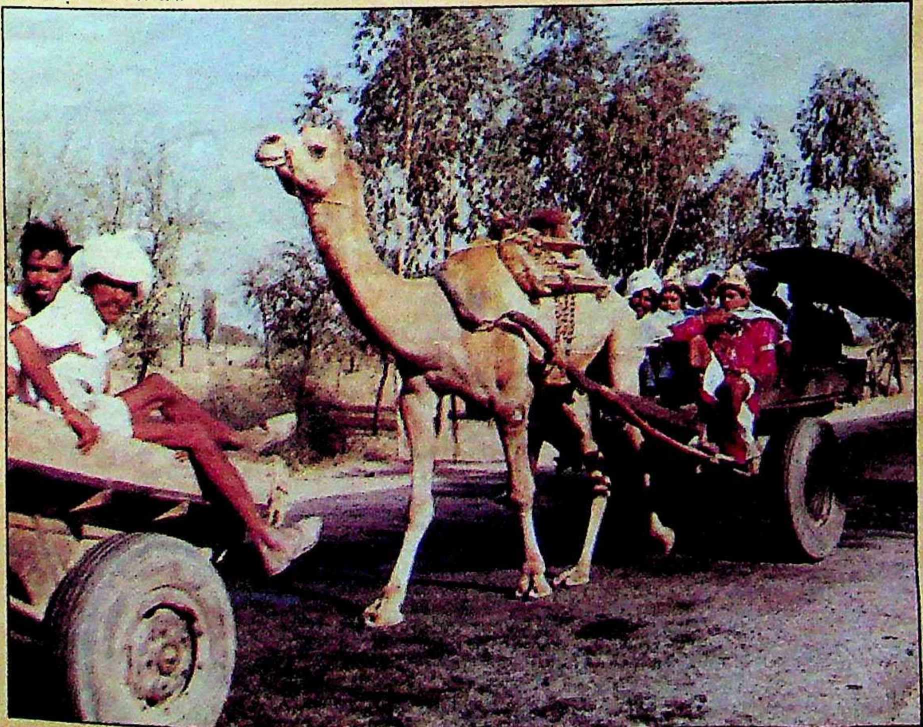

राजस्थान सरकार के महिला, शिशु एवं पोषाहार विभाग नें इस संदर्भ में अपने कार्यक्रम में केवल एक पंक्ति जोड़कर अपना काम पूरा समझ लिया है। यह पंक्ति महिला विकास कार्यक्रम और सामाजिक चेतना शीर्षक के तहत दर्ज है। इबारत यों है: "कार्यक्रम का एक प्राथमिक उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में चेतना जाग्रत करना है। जैसे कम उम्र के बच्चों की शादी।"

आखातीज यानी अक्षय तृतीया के दिन जब राजस्थान के गांवों में बाल विवाह धड़ल्ले से हो रहे थे, तो महिला, शिशु एवं पोषाहार विभाग जयपुर में गोष्ठी कर रहा था। इस विभाग की निदेशक डा० मालविका पंवार ने एक प्रेस बयान में कहा कि बाल विवाहों को रोकने के लिए जयपुर में गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में विभाग की राज्यमंत्री कुमारी गिरिजा व्यास, पुलिस महानिदेशक डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया और महिला संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राजस्थान की कुछ जातियों में व्याप्त इस कुप्रथा के संबंध में राज्य सरकार ने कोई अध्ययन भी नहीं करवाया है। दिल्ली की 'कौंसिल फार सोशल डेवलपमेंट' ने राजस्थान में बाल विवाहों का १९८६ में जरूर अध्ययन किया था। सुश्री अनीता दिघे के इस अध्ययन में राजस्थान में बाल विवाहों को सामाजिक परंपरा कहा गया है। इस परंपरा का निर्वाह अनुसूचित जाति एवं जन जाति व पिछड़ी जातियों में विशेष रूप से होता है। उनके अध्ययन के अनुसार बाल विवाह और 'नाता' (विधवा-विवाह का एक प्रकार) जैसी परंपराएं ब्राह्मण, बनियों, राजपूतों और जैनियों में नहीं रहीं।

अध्ययन के अनुसार कुछ जातियों में बाल विवाह की प्रथा इसलिए प्रचलित है, क्योंकि इसमें कम खर्च से एक साथ कई विवाह कर देने की सुविधा है। आखातीज का दिन चुने जाने का कारण यह है कि शादी के मुहूर्त के लिए किसी पंडित को नहीं पूछना होता और फसल कट चुकी होती है।

—आलेख : ओम सैनी

—छाया : प्रताप सिंह

पांच रुपए के नये नोट

क्या ये नोट जाली हैं ?

असंदिग्ध

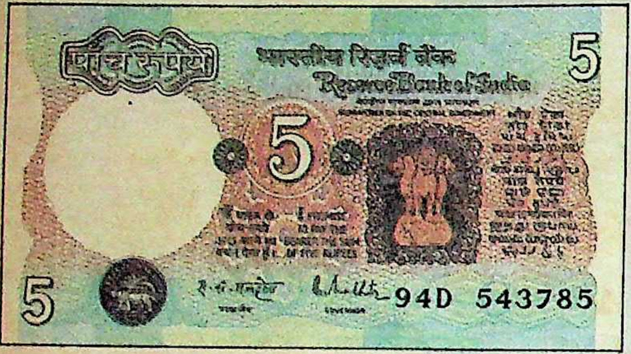

संदिग्ध

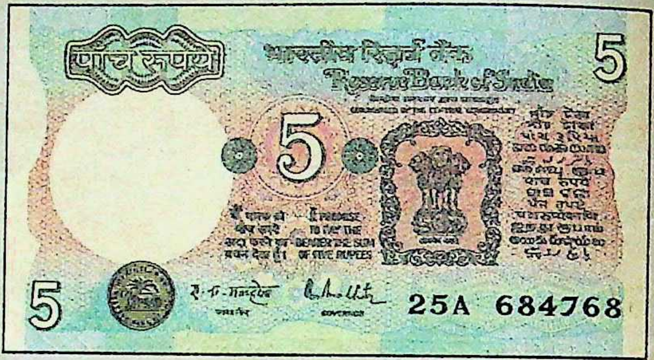

पूरे भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों धड़ल्ले से चलनेवाले, पांच रुपए के उन नोटों को नकली करार दिया जा रहा है जो देखने में तो हूबहू असली लगते हैं, लेकिन उनके मुद्रण में कई विभिन्नताएं हैं। इन नोटों के नकली होने की आशंका तब और भी बढ़ जाती है, जब खुद भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी इन्हें असली कहने से कतराते हैं। अलबत्ता, इन नोटों की विभिन्नताओं को देख भारतीय रिजर्व बैंक के ही एक अधिकारी का कहना है, "मुझे ये नोट जाली लगते हैं। लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होनेवाला। कुछ दिनों पूर्व, सौ रुपए के जाली नोटों का मामला भी हमारी जानकारी में आया था। सामान्य दृष्टि से देखने पर वे नोट बिलकुल असली लगते थे, मगर जब उन्हें जांच के लिए बंबई भेजा गया, तब वे नकली साबित हुए।"

दूसरी ओर, लखनऊ स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के 'करैंसी' अधिकारी एएम गर्ग इन नोटों को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं। उनका कहना है, "अभी मैं न तो इन्हें असली कह सकता हूं और न ही नकली। इसका सही पता तो जांच के बाद ही लग सकता है।" उनके इस कथन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ मिलकर ऐसे तथ्यों को बल दिया है जो जाली नोट छापकर अपने देश के अर्थतंत्र को खोखला करने में जुटे एक संगठित गिरोह से संबंधित हैं। पांच रुपए के इन नोटों में यद्यपि तमाम विभिन्नताएं हैं, तथापि आसानी से वे पकड़ में नहीं आतीं। लेकिन यदि पांच रुपए के ही अन्य नोटों के साथ (जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी दावे के साथ असली बताते हैं) उपरोक्त नोटों का मिलान किया जाये, तो वे विभिन्नताएं एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। (देखें बाक्स) विश्लेषण की सरलता के लिए आगे विभिन्नताओं से परिपूर्ण नोटों को हम 'एक्स' नोट लिख रहे हैं।

शक की बुनियाद : इन दिनों पांच रुपए के

'एक्स' नोटों में विभिन्नताएं

पांच रुपए के 'एक्स' किस्म के नोटों में इसी मूल्य के अन्य नोटों की अपेक्षा सबसे बड़ी असमानता अशोक के स्तम्भ के आकार, उसके रंग परिवर्तन तथा उसकी पृष्ठभूमि के रंग परिवर्तन को लेकर है। यह बात शक का कारण तब बन जाती है, जब भारतीय रिजर्व बैंक के प्रदेश मुख्यालय पर बैठे अधिकारी यह कहते हैं, "इस परिवर्तन के संबंध में हमारे पास कोई अधिसूचना नहीं आयी है।" नीचे अंतर का विवरण दिया जा रहा है :

असली नोट	'एक्स' नोट
१. नोट में छपा अशोक का स्तंभ गुलाबी रंग का है और उसका आकार बड़ा है।	१. इसमें अशोक का स्तंभ हरे रंग का छपा है और उसका आकार छोटा है।
२. अशोक के स्तंभ की पृष्ठभूमि का रंग हरा है।	२. रंग गुलाबी है। पृष्ठभूमि की डिजाइन भी परिवर्तित है।
३. हर नोट की संख्या पटल की पृष्ठभूमि में 'सेल्फ डिजाइन' में कोई-न-कोई 'वर्ण' छपा होता है। जैसे, अंग्रेजी का 'ए', 'बी', 'जी' आदि। उदाहरण के लिए ९४-डी-५४३७८५ नम्बर का नोट देखें। इसमें '५४' के ठीक पीछे 'सेल्फ डिजाइन' में अंग्रेजी का 'जी' वर्ण छपा है।	३. इन नोटों की संख्या पटल की पृष्ठभूमि में कोई 'वर्ण' नहीं होता। यह 'एक्स' किस्म के नोटों की अहम पहचान है।
४. नोट के बीच में जहां एक गोले के भीतर बड़े अक्षर में '५' छपा रहता है, उसके दोनों ओर हरे रंग के छोटे-छोटे दो अन्य गोले बने होते हैं। इन गोलों की डिजाइन पर ध्यान दें।	४. हरे रंग के गोलों के भीतर की डिजाइन में काफी परिवर्तन हैं।
५. बायीं ओर एक गोल घेरे में शेर है और नारियल के पत्ते सफेद हैं तथा गोल घेरे में अंग्रेजी में 'रिजर्व बैंक आफ इंडिया' लिखा है।	५. इन नोटों के गोल घेरे में शेर है, लेकिन नारियल के पत्ते काले हैं तथा ऊपर हिन्दी में तथा नीचे अंग्रेजी और हिंदी में 'रिजर्व बैंक आफ इंडिया' लिखा है।
६. नोट पलटने पर दिखनेवाले ट्रैक्टर का सायलेन्सर (चिमनी) पतला है।	६. इन नोटों में छपे ट्रैक्टर का सायलेन्सर (चिमनी) काफी मोटा नजर आता है।

ये 'एक्स' नोट प्रदेश के बाजारों में पूरी तरह फैल चुके हैं। आलम यह है कि पांच रुपए के सौ नोटों को यदि अलग-अलग स्थानों से एकत्र किया जाये, तो उनमें दस नोट 'एक्स' किस्म के देखे जा सकते हैं। गंभीर बात तो यह है कि पिछले कई महीनों से बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से चल रहे इन 'एक्स' नोटों की विभिन्नताओं की ओर जिम्मेदार विभाग या बैंक अधिकारियों का ध्यान ही नहीं गया। उल्लेखनीय है कि जब कभी भी कोई नया नोट चलता है अथवा किसी नोट की डिजाइन, रंग-संयोजन या कागज आदि में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक क़ोई भी परिवर्तन करने से पूर्व उसकी बाकायदा अधिसूचना जारी करता है। उस अधिसूचना में नोट में होनेवाले परिवर्तनों का बारीकी के साथ उल्लेख होता है।

२५ अगस्त, १९८८ को भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच रुपए के नोट में किये गये परिवर्तन के संबंध में ऐसी ही एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था, "भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर राना मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ पांच रुपए के नोटों की नयी श्रृंखलाएं जारी करेगा। निम्नलिखित परिवर्तनों को छोड़कर ये नोट सभी तरह से इन मूल्य वर्गों के वर्तमान नोटों के समान होंगे। उपर्युक्त परिवर्तन इस प्रकार होंगे : नोट पर संख्या पटल में बड़े अक्षरों में 'वर्ण' 'जी' होगा।"

दिसम्बर, १९८८ में इसी प्रकार की एक अन्य अधिसूचना जारी की गयी थी। उसमें कहा गया था, "पांच रुपए के नोट में अशोक के स्तम्भ के नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा होगा।"

भारतीय रिजर्व बैंक की लखनऊ शाखा के करैंसी अधिकारी गर्ग बताते हैं, "इसके अतिरिक्त कोई भी अधिसूचना हमारे पास नहीं भेजी गयी है।" उनका यही कथन 'एक्स' नोटों को और भी अधिक संदिग्ध बना देता है, क्योंकि इन नोटों में अशोक के स्तम्भ, उसकी पृष्ठभूमि के रंग आदि में ऐसे कई परिवर्तन हैं, जिनका उपर्युक्त अधिसूचनाओं में किसी प्रकार का कहीं जिक्र नहीं। मसलन, 'एक्स' नोटों में अशोक का स्तम्भ हरे रंग में छपा है और उसकी पृष्ठभूमि का रंग गुलाबी है। अशोक का स्तम्भ भी काफी छोटा है। जबकि पांच रुपए के अन्य नोटों में स्थिति इसके विपरीत है। उनमें अशोक का स्तम्भ गुलाबी रंग में छपा है तथा उसकी पृष्ठभूमि का रंग हरा है। सवाल यह है कि यदि 'एक्स' किस्म के नोटों में इतना बड़ा परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक ने ही किया, तो उसने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी क्यों नहीं की ? और यदि जारी की, तो उसकी प्रति गर्ग के पास क्यों नहीं पहुंची ? सवाल तो यह भी है कि अगर 'एक्स' किस्म के नोट भारतीय रिजर्व बैंक ने ही जारी किये हैं, तो उसी के जिम्मेदार अधिकारी इन नोटों को असली कहने में क्यों कतरा रहे हैं ?

असमंजस क्यों ? : 'माया' ने इस संबंध में व्यापक छानबीन की है। छानबीन के दौरान 'माया' ने कुछ वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के आगे पांच रुपए के 'एक्स' नोट तथा पांच रुपए के ही अन्य नोट रखकर उनसे दोनों में अन्तर जानना चाहा। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया लखनऊ के उपक्षेत्रीय प्रबंधक जेएस मिश्रा ने 'एक्स' प्रकार के नोटों को ध्यान से परखने के बाद कहा, "बारीकी से ध्यान देने पर पता चलता है कि ये नोट नकली हैं। लेकिन यदि इन नोटों की विभिन्नताओं की ओर हमारा ध्यान न जाये, तो हम भी इन्हें असली समझने के लिए बाध्य हो जायेंगे।"

इसी बैंक के एक अन्य उपक्षेत्रीय प्रबंधक प्रेमकांत बाजपेई कहते हैं, "ये नोट देखने में तो असली जैसे लगते हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 'गड़बड़' नोट हैं।" बाजपेई के सहकर्मी नरेश कुमार कपूर उनकी बात की पुष्टि करते हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के लखनऊ मुख्यालय में तैनात एक अधिकारी ने अपना नाम न छापने के अनुरोध के साथ कहा, "जब हमने इन नोटों की विभिन्नताओं की ओर ध्यान दिया, तभी पता चला कि ये नोट 'सही' नहीं हैं। वरना, उसके पहले तो इस तरह के न जाने कितने नोट हमारे हाथ से ही चल गये होंगे।"

इन दिनों
पांच रुपए के ये 'एक्स'
नोट प्रदेश के बाजारों में पूरी तरह
फैल चुके हैं।

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक पीएम त्रिपाठी की 'एक्स' किस्म के नोट को देखने के बाद टिप्पणी थी, "कागज देखकर इसे नकली नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनमें जो परिवर्तन हैं, उनके विषय में यदि कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये नोट नकली होंगे। इन परिवर्तनों को देखकर उत्पन्न होनेवाली भ्रांतियों का निवारण होना जरूरी है।"

यही नहीं, वरन इन नोटों की विभिन्नताएं देखने के बाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी चौकन्ने हो चुके हैं। अर्थ विषयक अधिसूचना एवं अनुसंधान संगठन के पुलिस अधीक्षक सीएसजे दास ने 'माया' से कहा, "प्रदेश में जाली नोटों के चलन की अभी हमें कोई ताजी सूचना प्राप्त नहीं हुई। लेकिन पांच रुपए के इन नोटों को बारीकी से देखने के बाद मुझे भी लगता है कि ये जाली नोट हैं। कुछ समय पहले हमें सूचना मिली थी कि इलाहाबाद में डफरिन अस्पताल के सामने एक मकान में फर्जी नोट छापने का एक छापाखाना है। हम कोई कार्रवाई करते इससे पूर्व ही वह वहां से गायब हो गया। शायद गिरोह को इसकी खबर मिल गयी थी कि हमें उसके विषय में जानकारी मिल चुकी है। यह मामला देशहित का है। आप इसे जरूर छापिए।"

खतरनाक साजिश : दरअसल, जानकार सूत्रों के मुताबिक, इन दिनों उत्तर प्रदेश में जाली नोट छापनेवाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह वही गिरोह है, जिसके कुछ सदस्य जुलाई, १९८८ में जौनपुर जिले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जौनपुर पुलिस ने इस गिरोह के ४ लोगों को जाली नोटों तथा उन्हें छापने की सामग्री सहित गिरफ्तार किया था। लेकिन पकड़े गये लोगों में गिरोह का कोई मुख्य सदस्य नहीं था। बड़ी मछलियां पुलिस के जाल में नहीं फंस पायीं। पुलिस ने भी मात्र इन्हीं ४ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके देशहित के इस गम्भीर मामले में तहकीकात की इतिश्री मान ली।

विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इसी गिरोह ने अब लखनऊ में अपना मुख्यालय बना लिया है। इस धंधे की जड़ें अब काफी गहरी हो चुकी हैं। कमोबेश पूरा प्रदेश जाली नोटों की चपेट में है। 'माया' को इस धंधे की खबर इस गिरोह का शिकार बने एक युवक से मिली।

"साहब, अगर हमारा नाम छप गया, तो 'वे लोग' मुझे गोली मार देंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके पास बेशुमार दौलत है...पहुंच भी ऊपर तक है।" अपना नाम न छापने की शर्त पर उस युवक ने कई महत्वपूर्ण और चौंकानेवाले तथ्य उजागर किये। उसने बताया, "गिरोह का मुख्यालय लखनऊ से लगभग तीस किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर है जो तीन जिलों (लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी) की सीमा पर स्थित है। इस गिरोह में ऐसी हस्तियां शामिल हैं, जिन पर पुलिस की कार्रवाई बेअसर हो सकती है। गिरोह के कुछ सदस्य तो ऐसे लोग हैं, जिनके कंधों पर देश और समाज की जिम्मेदारियां हैं।" नोटों की छपाई कहां होती है ? यह जानकारी ठीक तरह से उस युवक को भी नहीं। उसने बताया, "छापाखाना शायद पटना में लगा है।"

कार्यपद्धति : जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के २५ से भी अधिक जिलों में इस गिरोह के सदस्य अपना जाल बिछाये हुए हैं। लखनऊ में इस गिरोह से संबद्ध व्यक्ति मूलतः सोने-चांदी का व्यापारी है। पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित नाले के पास किसी मकान को उसने अपना अड्डा बना रखा है। इस व्यक्ति ने अपने मातहत लगभग आधा दर्जन एजेंट नियुक्त कर रखे हैं। एजेंटों का काम ऐसे जरूरतमंद बेरोजगारों की तलाश करना है जो अपनी थोड़ी बहुत रकम लगाकर इस धंधे में शामिल हो सकते हों।

गिरोह के सदस्य शुरू में एजेंट के माध्यम से इन जरूरतमंद बेरोजगारों से हजार-पांच सौ रुपए की छोटी रकम लेकर उसकी तिगुनी रकम के नकली नोट उन्हें दे देते हैं। इस प्रक्रिया में खास बात यह होती है कि एजेंट लोग केवल सौ-पचास रुपए के नोटों के रूप में ही रकम लेते हैं, जबकि उसके बदले

में वे जो तिगुनी रकम देते हैं, वह सिर्फ पांच रुपए के नोटों में होती है।

इस तरह जाली नोटों को बाजार में खपाने के लिए उन बेरोजगारों को मोहरा बनाया जाता है। इस काम के लिए जिस कार्यपद्धति को अपनाया जाता है, वह बहुत सरल है। सूत्रों के मुताबिक, गिरोह के संपर्क में आये व्यक्ति को विभिन्न बैंकों में खाते खोलने का निर्देश दिया जाता है। फिर वे इन खातों में भारी मात्रा में पांच रुपए के फर्जी नोट जमा करके, एक दो दिन बाद उतनी ही रकम निकाल लेते हैं। इस अवधि में उनके द्वारा बैंक में जमा किये गये नोट न जाने किस-किस के पास पहुंच चुके होते हैं।

पकड़ क्यों नहीं ? : इन नकली नोटों के पकड़े न जाने के कई कारण हैं। मसलन, छोटे मूल्य (पांच रुपए) का नोट होने की वजह से कोई भी व्यक्ति इन्हें ध्यान से देखे बगैर, रख लेता है। लेकिन यह बात केवल आम व्यक्ति पर ही लागू हो सकती है, बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों पर नहीं।

तब आखिर क्या वजह है जो ये जाली नोट बैंक—अधिकारियों की भी पकड़ से बाहर हैं? इस बारे में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, हजरतगंज (लखनऊ) के एक अधिकारी ने चौंकानेवाली जानकारी दी, "बैंक में यह नियम होता है कि जाली नोट पकड़ में आने पर उसे तत्काल जलाकर नष्ट कर दिया जाये। इसलिए जब कभी भी कोई जाली नोट नजर में आता है, हम उसे नष्ट कर देते हैं। हमारे 'मैनुअल' में भी यह बात दर्ज है।"

लखनऊ के अमीनाबाद स्थित स्टेट बैंक की शाखा में ऐसी एक घटना घट चुकी है। बताया जाता है कि दिसम्बर, १९८८ में एक बड़े ज्वैलर्स का मुनीम लगभग २० लाख रुपए उपरोक्त बैंक में जमा कराने पहुंचा था। इस रकम में छोटे-बडे सभी प्रकार के नोट शामिल थे। उनमें सौ रुपए के कई नोट जाली थे। बैंक अधिकारियों ने उपरोक्त ज्वैलर्स को बुलाकर उसके सामने उन नोटों को जलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली थी।

अन्य घटनाएं : सवाल यह है कि इस गिरोह का संचालन कौन कर रहा है? कहीं इसके पीछे किसी विदेशी एजेंसी का तो हाथ नहीं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी कई मिसालें भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने ब्रिटेन और अमरीका के आर्थिक ढांचे को ढहाने के उद्देश्य से अरबों की संख्या में फर्जी पौंड और डालर छापकर, वहां के बाजार पाट दिये थे।

सत्तर के दशक में एक खबर फैली थी कि कोई विदेशी एजेंसी भारतीय अर्थतंत्र की रीढ़ तोड़ने के लिए पांच सौ तथा हजार रुपए के फर्जी नोट छाप रही है। इस खबर की सचाई क्या थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस खबर के तत्काल बाद सरकार ने पांच सौ तथा हजार रुपए के नोटों का प्रचलन बंद कर, उन्हें वापस ले लिया था। जनता के जिन लोगों के पास ये नोट थे, वे जब इन्हें वापस करने बैंक में गये, तब उनसे बैंक में लिखित रूप से यह जानकारी मांगी जाती थी कि उन्हें वे नोट कहां से प्रापप्त हुए?

इसी प्रकार १९४५ में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय बाजारों में सौ रुपए के जाली नोटों की बाढ़ आ गयी थी और अंग्रेजों को सौ रुपए के नोट वापस लेने पड़े थे। इसके बाद देश में कई बार जाली नोटों के मामले प्रकाश में आये हैं। उनमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसलिए अब इतने वर्षों बाद जब पांच रुपए के जाली नोटों की खबर मिली है, तो यह कहना ठीक नहीं कि कोई छोटा-मोटा गिरोह महज अपने आर्थिक लाभ के लिए यह काम कर रहा है, क्योंकि तस्करों और विदेशी एजेंसियों के बीच चोली-दामन का रिश्ता पुराना है।

बहरहाल, बाजारों में तेजी से प्रचलन में आये ये 'एक्स' किस्म के पांच रुपए के नोट असली हैं या नकली, इसका निर्णय तो भारतीय रिजर्व बैंक के 'नासिक प्रेस' या डिपार्टमेंट आफ करेंसी, बम्बई के जिम्मेदार जांच अधिकारी ही कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस भ्रांति को दूर करने के लिए प्रदेश मुख्यालय में बैठे भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी क्या कर रहे हैं? यह स्थिति तब है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक तथा पुलिस की अर्थ विषयक शाखा तक के अधिकारी इन नोटों की असलियत के प्रति खुद सशंकित हैं।

—लखनऊ ब्यूरो

Kurlopillo तकिये

नर्म. सुखद. आरामदेह.

सीने से लगा लेने वाले दो प्रकार के नर्म, स्वप्नीले तकिये ड्रीमफ्लावर और कल्पना. क्या खूबसूरती! पूरी करे आपकी हर जरूरत

कर्ल-ऑन गद्दों के निर्माताओं की देन

कर्नाटक कंज्यूमर प्रॉड्क्ट्स् लि,
क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय व शोरूम:
1764, प्रताप स्ट्रीट चना मंडी, पहाडगंज, नई दिल्ली - 110 055. दूरवाणि: 732133, 772019; 109 375, आर.के. नगर, जी.टी. रोड, कानपुर 208 012. दूरवाणि: 243695 (पीपी); 88, न्यू टेक्स्टैल मार्केट, पंडेरी, रायपुर: 26, मंगल सदन, अनेकांत नगर, लिल्ली टॉकीज के पास, जहांगीराबाद, भोपाल 462 008. दूरवाणि: 67874; सी 23, सत्य शॉपिंग सेंटर, एम.जी. रोड, घाटकोपर (ई) बम्बई 400 077 दूरवाणि: 5113220; रोड नं. 6, दयाल मैंशन, राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर अस्पताल के सामने,|पटना 800 016. दूरवाणि: 57911.

वीपी सिंह : पारदर्शी विकल्प की छवि

—एस जयपाल रेड्डी

कर्नाटक की जनतादल सरकार के ध्वस्त होने से ऐसा विश्वास किया (या कराया) जा रहा है कि कांग्रेस के इस बड़बोले विकल्प में कोई दमखम नहीं है और वह राजीव गांधी जैसे सर्वमान्य नेतावाली कांग्रेस की अखंड शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। राजीव गांधी के विपरीत, जनतादल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ढुलमुल चालवाले नेता माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वीपी सिंह, आपसदारी बरतने के बजाय अड़ंगेबाजी करनेवाले सहयोगियों के बीच अपनी सहमति की राजनीति के खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा है? लोकसभा में जनतादल के प्रखर प्रवक्ता एस जयपाल रेड्डी इससे इनकार करते हैं। वे इस धारणा को तोड़ते हैं कि पिछले साल इलाहाबाद उपचुनाव के बाद वीपी सिंह जिन संभावनाओं के साथ उभरे थे, उन्हें वे खो चुके हैं। प्रस्तुत हैं, रेड्डी के विचार और तर्क:

आपरेशन ब्ल्यू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या के फलस्वरूप भारत की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति चिंतित देशवासियों ने १९८४ के संसदीय चुनाव में कांग्रेस को अस्सी फीसदी बहुमत से ज़िता दिया। श्रीमती गांधी की हत्या से उत्पन्न गहरी सहानुभूति के माहौल में, नहीं के बराबर राजनीतिक छविवाले राजीव गांधी को एकबारगी स्वच्छ छविवाले नेता के रूप में उछाला और प्रचारित किया गया। शीघ्र ही चुनाव में बुलंद बहुमत मिल गया, नतीजतन राजीव की यह भ्रामक छवि बनी रही। उनकी आकर्षक चितवन लोगों को मरीचिका की तरह भ्रमित करती रही। दरअसल, व्याकुल संहानुभूति के उस दौर में वे जादू की छड़ीवाले खूबसूरत राजकुमार जैसे दिखायी पड़े और लोगों को लगा कि पंजाब जैसी समस्याओं से देश को वे ही निजात दिला सकते हैं। सधे-मंजे पर्यवेक्षक और टिप्पणीकार भी अटकलें लगाने लगे कि राजीवजी न सिर्फ देश को खुशहाल २१वीं सदी में ले जायेंगे, बल्कि विपक्ष को लंबे समय तक लुंजपुंज भी बनाये रखेंगे। लेकिन तीन साल से भी कम समय में ही देशवासियों के 'दूध-शहद पाने के सपने' चकनाचूर हो गये और सबको एक राष्ट्रीय दु:स्वप्न सताने लगा।

गुणात्मक बदलाव: राजीव अब 'पुरानी घपलेबाजी और खूबसूरत धोखाधड़ी' के साथ पहचाने जाने लगे। पंजाब का मसला न सिर्फ और उलझ गया, बल्कि पहले से अधिक संहारक बन गया। आतंकवाद जम्मू-कश्मीर तक फैल गया। राजीव गांधी से कुछ करते-धरते तो बना नहीं, उलटे वे घोटालों और दलालियों की बाढ़ में डूब गये—मसलन बोफोर्स सौदेबाजी, परिवार के मित्र अजिताभ बच्चन द्वारा स्विट्जरलैंड में फ्लैट की खरीद, व्यवसायी ललित सूरी का विवादास्पद तेल एवं प्राकृतिक गैस सौदा आदि। फलत: कांग्रेस हरियाणा, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र और तमिलनाडु के चुनावी मैदान में चारों खाने चित हो गयी। चुनावों में हार-पर-हार से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की आग भड़क उठी। बिहार, राजस्थान और गुजरात में यह आग इस हद तक फैली कि भयभीत पार्टी हाईकमान समझौता-परस्त हो गया। इस तरह जहां राजीव गांधी का रंगीन गुब्बारा फूट गया, वहां राजनीतिक नजारे के दूसरे छोर पर, विश्वनाथ प्रताप सिंह इतने ऊपर उठे कि नयी राष्ट्रीय पार्टी जनतादल के नेता मान लिये गये। राजीव गांधी के जोरदार विकल्प के रूप में सिंह का उदय और जनतादल का बनना ऐसी सकारात्मक उपलब्धियां हैं, जिनमें भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए गुणात्मक बदलाव की संभावनाएं हैं।

जनतादल, ढांचे के तौर पर, १९७७ की जनता पार्टी के मुकाबले, दो ठोस कारणों से सुधरा हुआ सबल संगठन है। पहला कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने से अलग रखकर दल विचारधारा की दृष्टि से अधिक-

वीपी सिंह की छवि के पीछे उनकी पारदर्शी स्वच्छता है, इसलिए वह बिगड़ नहीं सकती।

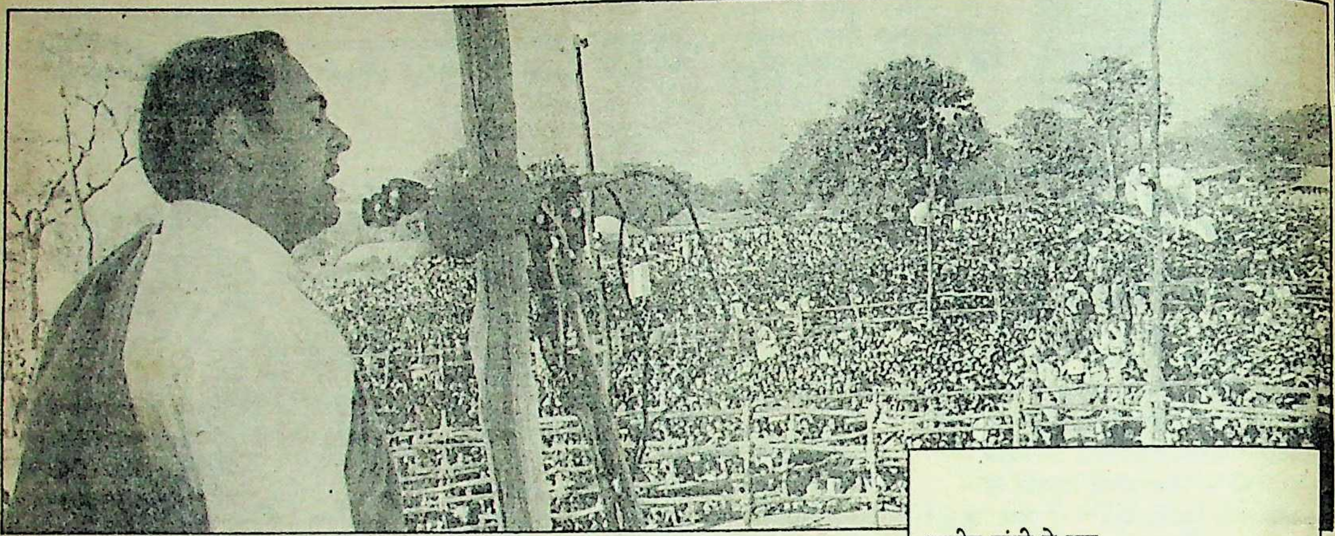

राजीव गांधी से कुछ करते-धरते तो बना नहीं, उलटे वे घोटालों और दलालियों की बाढ़ में डूब गये।

से-अधिक लोगों और राजनीतिक समूहों से जुड़ने में सक्षम हो गया है। दूसरा यह कि वीपी सिंह व्यापक स्तर पर जनतादल के नेता के रूप में स्वीकृत तथा प्रचारित हो गये हैं, जबकि जनता पार्टी नेतृत्व के मुद्दे पर सहमति के अभाव में बराबर झटके खाती रही। दल की इस सापेक्ष विशेषताओं के अलावा, १९७७ के मुकाबले ऐतिहासिक स्थितियां भी पर्याप्त परिपक्व हो गयी हैं। पिछले १२ सालों के अंदर कई राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकलकर विपक्ष के हाथ में चले गये। इसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी के प्रभाव का भौगोलिक विस्तार घटा और यह प्रभाव फिर बढ़ने की गुंजाइश नहीं रह गयी है।

इंका का पिरामिड : कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की गुणवत्ता पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से घटती जा रही है। पंडित नेहरू अपनी व्यक्तिगत महानता और राजनीतिक क्षमता, दोनों की बदौलत चोटी के नेता माने जाते थे। इंदिरा गांधी में महानता कम थी, पर वे अपनी क्षमता के कारण मानी-जानी जाती थीं। लेकिन राजीव गांधी में न महानता है न योग्यता-क्षमता। इनके पास जो कुछ है, विरासत में मिली सत्ता है। तथ्य यह है कि १९६९ से कांग्रेस की महंतशाही एक औंधा पिरामिड बन गयी है जहां तमाम उच्चाधिकार एक व्यक्ति में केंद्रित हो गये हैं। जब वह व्यक्ति इंदिरा गांधी थीं, तब उन्होंने सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के मामले में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कभी नहीं किया। लेकिन वे पार्टी और सत्ता के संपूर्ण ढांचे को अपनी इच्छा और सूझबूझ से जोड़े रख सकी थीं। जहां उनके प्रशासन की खामियों का व्यापक विरोध हुआ, वहीं उनके नेतृत्व और शासन-शैली को उनके आलोचकों तक ने सराहा। इस सिलसिले में जो चीज चौंकानेवाली है, वह यह है कि अपनी मां की देशी-विदेशी जागीर को गैरकानूनी तरीके से हथिया लेनेवाले राजीव गांधी स्वच्छता का दावा इतने इत्मीनान के साथ करते रहे कि बड़े-बड़े टिप्पणीकार भी इनके प्रधानमंत्रित्व के प्रारंभिक वर्षों में इस दावे को मान गये।

पर अब इनके दावे का खोखलापन उभर गया है। कुछ हलकों का यह खयाल कि इंदिरा गांधी को लोग व्यक्तित्व स्तर पर भ्रष्ट नहीं समझते थे, बदल गया है। उनके नेतृत्व को, उनके भ्रष्टाचार के रिकार्ड के बावजूद, दूसरे कारणों से तरजीह दी जाती थी। इसी तरह राजीव गांधी के मामले में कुछ पर्यवेक्षकों का यह मानना कि बोफोर्स सौदे जैसे भयंकर घोटाले उनकी व्यक्तिगत छवि को बिगाड़ नहीं पाये हैं, या तो नाउम्मीदी का इजहार है या सिर्फ चाहतभरा सोच। ऐसा नहीं है कि बोफोर्स घोटाला पृष्ठभूमि में चला गया है। दरअसल, यह भारतीय जनता के सामूहिक अवचेतन का ऐसा फोड़ा बन गया है जो बराबर बहता रहता है।

स्मरणीय है कि पांडिचेरी लाइसेंस घोटाले ने, जो बोफोर्स घोटाले की तुलना में मुर्गी का चारा था, आपातकाल का रास्ता खोला था, जिसकी बदौलत १९७७ में जनता पार्टी विजयी हुई। आज ठक्कर रिपोर्ट ने, हालांकि कांग्रेस की शव-पेटी में आखिरी कील नहीं ठोंकी है, बोफोर्स के कारण हुए घाव पर निश्चय ही नमक मल दिया है।

सफाये की तैयारी : हमारा समाज जापानी समाज की तरह विकसित नहीं है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गद्दी से उतार फेंके, लेकिन इतना काहिल भी नहीं है कि शिखर स्तर के भ्रष्टाचार को मात्र एक मुद्दे के रूप में मंजूर कर ले। दलील दी जा सकती है कि सही तौर पर व्यापक आक्रोश की राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए वैकल्पिक मशीनरी की जरूरत होती है। वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल इतनी तेजी से विकल्प के रूप में उभरा है कि दल और कांग्रेस के बीच ध्रुवीकरण पूरा हो गया है। अब जनता दल कम से-कम लोकसभा की ३०० से ज्यादा सीटोंवाले आठ राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक—में कांग्रेस के सफाये की तैयारी कर चुका है।

वीपी सिंह की छवि के पीछे उनकी जीवनभर की पारदर्शी स्वच्छता है, इसलिए वह बिगड़ नहीं सकती। अपनी राजनीतिक शैली की बदौलत वे विनम्र अवश्य दिखायी देते हैं, पर किसी भी माने में कमजोर नहीं हैं। वे विश्लेषण की हुज्जत से बचते हैं, पर राजनीतिक निर्णय लेने में अद्भुत सूझबूझ दिखाते हैं। अब तक के अपने क्रियाकलाप में उन्होंने जो निर्णय लिये, उनसे साफ है कि एकांत में निर्णय लेनेवाले वे अकेले आदमी हैं। बिना इंदिरा गांधी की जानकारी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इनका इस्तीफा देना, राजीव गांधी की नाराजगी के बावजूद वित्तमंत्री के रूप में इनका व्यावसायिक घरानों पर छापे जारी रखना, जब ये रक्षामंत्री थे तब एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी सौदे में दलाली की जांच के लिए इनका आदेश देना, राजीव मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का इनका फैसला, इलाहाबाद के चुनावी मैदान से अमिताभ बच्चन को भगाने में इनकी जवांमर्दी, जनतादल में शामिल होने की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देने में इनकी पहलकदमी और दलबदल विरोधी कानून से इनका तनिक भी न डरना, वीपी सिंह की निर्णय-क्षमता के जीवंत

उदाहरण हैं।

नजरिये की गलतफहमी. वीपी सिंह अपने वरिष्ठ सहयोगियों से अधिक दृढ़ता के साथ निबट सकते हैं, लेकिन सहयोगियों को वे अधिक सम्मान और सुविधा देना पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन पर, इंदिरा गांधी के अधिनायकवाद की तुलना में, नरम होने का आरोप लगाया जाता है। यह बात अकसर बिसार दी जाती है कि श्रीमती गांधी ने भी तथाकथित 'दुर्गा' बनने में छह साल लगाये थे। १९६६ से १९७१ तक के उन छह सालों के दौरान वे भी कमजोर और भ्रमित समझी जाती रहीं। ऐसे में यह आग्रह कहां तक उचित है कि वीपी सिंह मात्र छह महीनों के अंदर जनतादल का ढांचा और व्यवस्था दुरुस्त कर दें?

किसी भी बड़े युद्ध के सारे मोरचों पर एक ही पक्ष नहीं जीतता। पिछले दो वर्षों में कांग्रेस और विपक्ष के बीच जितने भी मुकाबले हुए उनमें विपक्ष विजयी रहा। एकमात्र कर्नाटक में लड़ाई हारने की बात कही जा रही है, वह भी सिर्फ इकाइयों द्वारा। इसकी हकीकत भी सामने आ जाती, बशर्ते बोम्मई सरकार को विधानसभा में २७ अप्रैल को शक्ति-प्रदर्शन का अवसर दिया गया होता। पर यह मौका ही नहीं दिया गया और कर्नाटक के राज्यपाल ने राजीव गांधी के लिए येन-केन-प्रकारेण यह लड़ाई जीत ली। सच तो यह है कि यदि राज्यपाल प्रतिकूल हो जाये, तो भी कोई राज्य सरकार—चाहे वह बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र—नहीं टिक सकती। दूसरी ओर, पिछले दो वर्षों में कांग्रेस अपने आप इतनी लड़ाइयां हार चुकी है कि कर्नाटक में षड्यंत्र से हासिल उसकी कामयाबी भी 'युद्ध की निर्णायक विजय' के रूप में उछाली जा रही है। यह नजरिये की गलतफहमी ही है कि ऐसी बातें न केवल बुरी तरह गिरे मनोबलवाली कांग्रेस उछालती है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया की कठोर प्रकृति देखना पसंद न करनेवाले अधीर बुद्धिजीवी भी उसकी हां-में-हां मिलाते हैं।

कांग्रेस अपनी हस्ती और होनहारी राजीव गांधी में ही पाती है, जबकि जनतादल और शेष विपक्ष को उनसे अपना पावना वसूलना है। वीपी सिंह तुलना और विपरीतता दोनों से निखर उठते हैं। जनसामान्य की पसंद राजीव गांधी के विरोध और वीपी सिंह के पक्ष में बन चुकी है। बुद्धिजीवी अपनी मर्जी से चाहे जितना भी समय लगायें, पर जब लड़ाई के मोर्चे स्पष्ट हो जायेंगे तब वे भी अपना १९८० का रुख बदल देंगे। अगले चुनाव के वक्त कांग्रेस में भगदड़ मचनी-ही-मचनी है और तब वे (बुद्धिजीवी) समझ जायेंगे कि यह पार्टी टूट-बिखर गयी और गैरकांग्रेस सरकार के लिए सबल-सुयोग्य प्रतिपक्ष बनाने के लायक भी नहीं रही।

◆

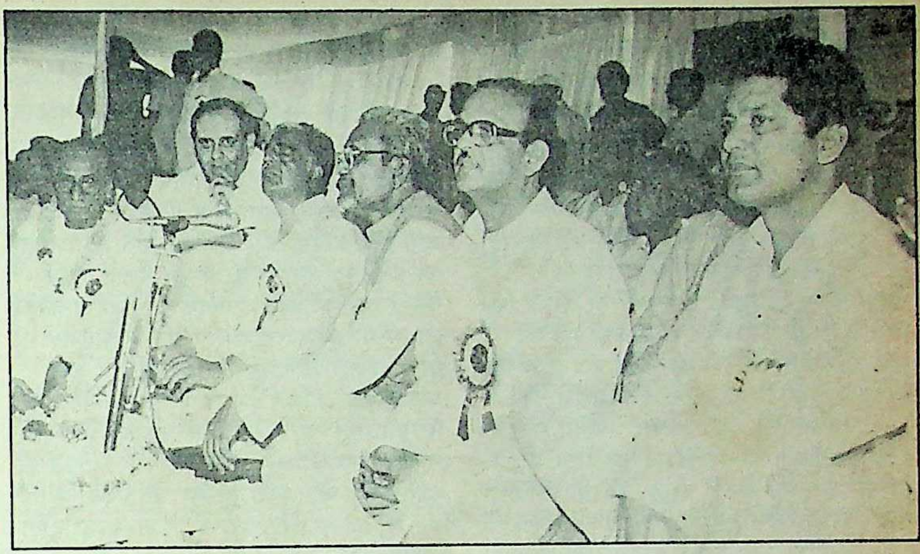

विपक्ष जनसमर्थन खो रहा है

—डा० जय दुबाशी

क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस-इ के समक्ष विपक्ष का हौवा खड़ा करने में सफल हुए हैं? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो कोई भी ईमानदारी से देने को तैयार नहीं। फिर पिछले एक साल में जिस तेजी के साथ विपक्ष की स्थिति बनती-बिगड़ती रही है, उसे मद्देनजर रखते हुए किसी निर्णय पर पहुंच पाना आसान बात नहीं। शायद यही वजह है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक भी ढुलमुल नजरिया पेश करने पर मजबूर हैं। किंतु पिछले एक साल में कांग्रेस-इ और विपक्ष की बदलती स्थितियों का करीब से जायजा लेनेवाला यह कहते नहीं चूक सकता कि यदि आजकल में चुनाव करा दिये जायें, तो एक बार फिर राजीव गांधी अपनी सरकार बनाने में सफल हो जायेंगे। यह बात और है कि इस बार उन्हें या उनकी पार्टी को पांच साल पहलेवाला व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं होगा। जहां तक विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात है, तो उनकी मौजूदा स्थिति तो बिलकुल उस आदमी-सी है जो बस के इंतजार में घंटों बस स्टैंड पर खड़ा रहता है और जब बस आती है, तो वह उस पर चढ़ नहीं पाता। ऐसे में वह व्यक्ति सिवाय हाथ मलने के और क्या कर सकता है?

बदलता नजरिया: मजे की बात तो यह है कि यदि अब से डेढ़-दो माह पूर्व इस तरह का आकलन पेश किया जाता, तो लोग मजाक उड़ा सकते थे, किंतु आज परिस्थितियां विपक्ष के इतनी प्रतिकूल हो गयी हैं कि लोग अपनी धारणा बदलने को मजबूर हैं। वर्तमान राजनीतिक माहौल को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैराल्ड विलसन के उस कथन की याद आती है कि राजनीति में एक महीने का समय थोड़ा नहीं होता। इतने समय में तो पासा पलट जाता है। यदि पिछले डेढ़-दो माह के बीच के कांग्रेस-इ के कारनामों का जायजा लिया जाये, तो पता चलता है कि कांग्रेस ने इस अवधि में जो कुछ किया, उसे अहम राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता था, किंतु विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे विपक्ष नें कांग्रेसी कारगुजारियों पर गलत ढंग से वार किया। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उलटे विपक्षं को ही नुकसान उठाना पड़ा।

मिसाल के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित ठक्कर रिपोर्ट के लीक होने पर जो बावेला मचाया गया, वह सिरे से गलत था, क्योंकि भारतीय मतदाता की इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह श्रीमती गांधी के असली हत्यारे की जानकारी हासिल करे।

यही नहीं, प्रधानमंत्रियों और राजाओं की मौतें भी ब्रह्मांड की प्रक्रिया के ही अंतर्गत आती हैं, इसलिए श्रीमती गांधी की मौत को मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रंयास

करना उचित नहीं लगता। आखिर अमरीका के राष्ट्रपति कैनेडी की भी तो हत्या हुई थी, उनकी हत्या से संबंधित वारेन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर अमरीका में हंगामा क्यों नहीं हुआ? फिर यदि ठक्कर रिपोर्ट को राजनीतिक मुद्दा बनाना ही था, तो कम-से-कम आगा-पीछा तो सोचा होता। बिना किसी चीज की गहराई में जाये, उसको उछालना क्या परिपक्व राजनीति का द्योतक है? सचाई तो यह है कि जिस गलत ढंग से विपक्ष ने बोफोर्स मुद्दे को उछाला, उससे कहीं ज्यादा गलत ढंग से विपक्ष ने ठक्कर रिपोर्ट को भुनाने की कोशिश की।

राजनीतिक अपरिपक्वता : किसी बात को राजनीतिक मुद्दा बनाने से पूर्व इस सत्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि बोफोर्स और ठक्कर रिपोर्ट जैसे मुद्दों का भारत की थकी-हारी जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पडता। फिर भारतीय समाज का तो ऐसा नैतिक पतन हुआ है कि यहां 'हीरो' या 'विलेन' की खोज निरर्थक साबित होगी। क्योंकि यहां जो भी है उत्पीड़ित है, शोषित है, तिरस्कृत है। ठक्कर रिपोर्ट को उछाला गया, तो उससे नतीजा क्या हासिल हुआ? यही न कि न्यायमूर्ति ठक्कर कांग्रेसी दिग्गजों का निशाना बने और देखते-ही-देखते एक न्यायमूर्ति राजनीतिक चक्रव्यूह की भेंट चढ़ गया? इसी तरह कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई या रामकृष्ण हेगड़े का कुछ नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस का निशाना विपक्ष था। विपक्षी सरकार गिरने से नुकसान विपक्ष को ही हुआ और चूंकि विपक्ष के अग्रणी विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि कर्नाटक खेल का खमियाजा 'राजा मांडा' के सिर पड़ा। स्थिति तो यह है कि बोम्मई आज तक यह नहीं जानते कि उनकी टांग किसने और क्यों खींची? यही नहीं, उनकी टांग खींचनेवाले रामकृष्ण हेगड़े भी बोम्मई के हटने पर पूरी तरह संतुष्ट हैं।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के हादसे से पूर्व विपक्ष की स्थिति कुछ बेहतर हो चली थी। यदि मतों के प्रतिशत के ब्यौरे को ध्यान मे रखा जाये, तो पिछले कुछ सालों में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की उठती-गिरती स्थिति की तस्वीर साफ हो जाती है। ब्यौरे पर नजर दौड़ाने से पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत में जिसके पास मत है, उसके पास सत्ता नहीं तथा जिसके पास सत्ता है उसके ज्यादा समर्थक नहीं हैं। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि भारतीय मतदाताओं का ७० प्रतिशत भाग किसानों का है तथा इस ७० प्रतिशत भाग पर वह ३० प्रतिशत भाग हुकूमत करता है जिसकी अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से गैरकृषि स्रोतों पर निर्भर है? चूंकि आजादी के समय से ही कांग्रेस गरीब और अमीर को साथ रखकर चलने की कला में निपुण थी, इसलिए उसे सत्ता हासिल करने में कभी कठिनाई नहीं हुई। दूसरी वजह यह रही कि विपक्ष कभी एकजुट भी नहीं रहा। यदि इमरजेंसी के बाद ('७७) भी विपक्ष एकजुट न होता, तो उसे सत्ता आसानी से न मिलती। जहां तक कांग्रेसी वोट बैंक की बात है, तो यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि देश के १० प्रतिशत उच्चवर्ग का सहयोग कांग्रेस को हमेशा प्राप्त रहा। साथ में २० प्रतिशत मतदातावाले निम्नवर्ग, जिसमें हरिजन और अल्पसंख्यक शामिल हैं, पर भी कांग्रेस की सदा गिरफ्त बनी रही। नतीजतन अब तक ३० प्रतिशत मत की तो कांग्रेस को कोई दिक्कत ही नहीं रहती थी। चूंकि सरकार बनाने के लिए ४० से ४५ प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती है, इसलिए शेष १० से १५ प्रतिशत मत शेष रह गये ७० प्रतिशत किसान मतदाताओं में से हासिल करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर किसानों को लुभाने के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम काफी था जिनकी विकास की योजनाओं ने भारतीय मतदाता पर अलग-थलग छाप छोड़ रखी थी। किंतु आज जो स्थिति है वह काफी बदली हुई है। देश का उच्चवर्ग, जिसमें अब मध्यमवर्ग के लोग भी शामिल हो रहे हैं, काफी होशियार हो गया है। अब तक चूंकि व्यापार और उद्योग को सुदृढ आधार देने की बात थी, इसलिए कोई कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, किंतु चूंकि अब समय के साथ उनके पैर जम गये हैं, इसलिए वे भी अब तभी तक खामोश रहने के लिए तैयार हैं, जब तक केंद्र में बैठी सरकार उनका अहित न सोचे। उच्चवर्ग में शामिल 'नये अमीर', जो हर समय अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे नेता की जरूरत महसूस कर रहे हैं जो उन्हीं के बीच से उठकर शीर्ष पर पहुंचा हो। इस तलाश का कारण यह है कि उच्चवर्ग कांग्रेस को अपना हितचिंतक न मानने पर मजबूर हो गया है। उसे एक विकल्प की आवश्यकता है। यानी उच्चवर्ग जो अब तक कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है, उसने कांग्रेस से कतराना शुरू कर दिया है।

असंतोष : दूसरी ओर निम्नवर्ग भी कांग्रेस से काफी असंतुष्ट है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पुनः सत्तासीन होने की खातिर हिंदू कार्ड खेलने का मन बना चुकी है। ऐसे में अल्पसंख्यकों का कांग्रेस से विमुख होना लाजिमी है। यही नहीं, हरिजन भी कांग्रेस से काफी असंतुष्ट हैं। आज जितना वीपी सिंह की ओर वे आकर्षित हो रहे हैं, उतना राजीव की ओर नहीं। इसका एकमात्र कारण यह है कि वर्षों से भूमिहीन रहकर शोषण सहते-सहते वे ऊब चुके हैं। उन्हें 'राजा मांडा' की भूमि संबंधी घोषणाओं में दम नजर आता है। इस तरह से निष्कर्ष यह निकलता है कि अब कांग्रेस के पास उच्चवर्ग का सिर्फ ५ प्रतिशत तथा निम्नवर्ग का केवल १० प्रतिशत आधार बाकी रह गया है। यानी पहले के ३० प्रतिशत के मुकाबले कांग्रेस के पास अब केवल १५ प्रतिशत ही निश्चित मत रह गये हैं। जाहिर है, यह स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के ३० प्रतिशत वोट बैंक में से १५ प्रतिशत मत विपक्ष की ओर खिसक गया है। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को ७० प्रतिशत किसान मतदाता में से २५ से ३० प्रतिशत को लुभाना पड़ेगा। यानी प्रत्येक दो मतदाताओं में से एक का समर्थन प्राप्त करना जरूरी है। बिलकुल यही स्थिति १९७७ में बनी थी। उस समय भी उच्चवर्ग और निम्नवर्ग असंतुष्ट हो गये थे। नतीजतन हजार हाथ-पैर मारने के बावजूद कांग्रेस को सत्ता छोड़नी पड़ी थी।

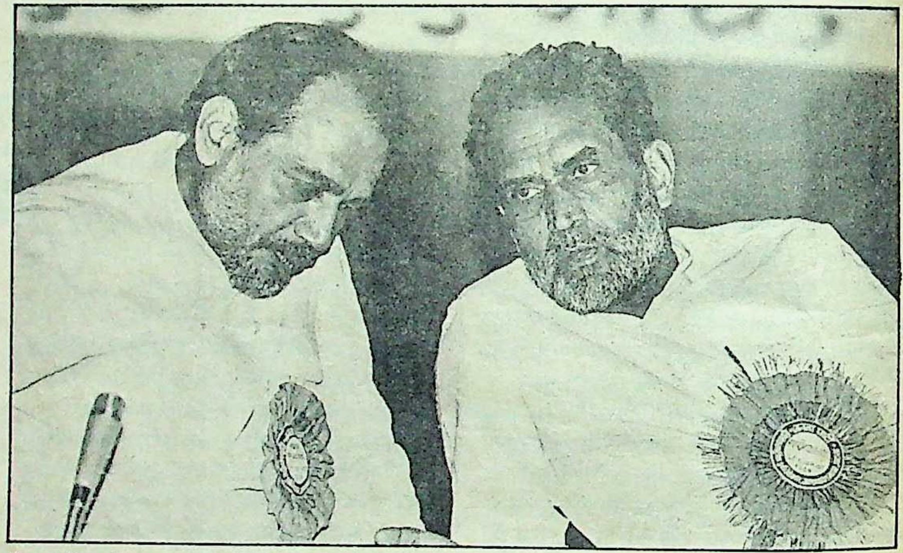

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के मतदाताओं के जेहन में कभी राजीव बनाम राजा या 'मिस्टर क्लीन' बनाम 'मिस्टर नाट सो क्लीन' की तस्वीर उभरी ही नहीं। हालांकि राजा ने अपने हथकंडों से इस बात की पूरी कोशिश की कि राजीव गांधी और उनके बीच एक ऐसी स्पष्ट रेखा नमूदार हो जो जनता को इस बात का अहसास कराये कि लड़ाई राजीव और वीपी सिंह की नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और ईमानदारी की है। यह सच है कि देश की आवादी का बहुत बड़ा भाग बोफोर्स घोटाले को लेकर स्तब्ध था, किंतु वह आज भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद बोफोर्स घोटाले में भागीदार थे। यह कोई नयी बात नहीं। नेहरू घराने के प्रति जनता का सोच सदा ऐसा ही रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैरों, मालवीय और बीजू पटनायक जैसे लोग दोस्त थे, किंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह पंडित जी पर उंगली उठा सके। बिलकुल यही स्थिति श्रीमती गांधी के साथ थी। हालांकि बोफोर्स घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री का नाम काफी उछाला गया और उनके साथियों पर भी उंगली उठायी गयी, किंतु जनता का नजरिया यही रहा कि संभव है उनके साथियों का घोटाले में कुछ हिस्सा रहा हो, किंतु प्रधानमंत्री स्वयं उस घोटाले में शामिल नहीं।

दूसरी ओर वीपी सिंह के बारे में सिर्फ यही धारणा नहीं बनी कि उनका किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं, बल्कि यह भी माना गया कि वीपी सिंह ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। हां, यह जरूर है कि वे अपने तुनकमिजाज साथियों को नियंत्रित नहीं रख पाते और अल्पसंख्यकों से बातचीत के दौरान समझौतावादी नजरिया अपनाते हैं। यही वजह है कि वे कभी हाजी मस्तान के साथ देखे जाते हैं, तो कभी बाल ठाकरे के साथ। वीपी सिंह का करीब से जायजा लेनेवाले शायद इसीलिए ढुलमुल नजरिया बना बैठते हैं। क्योंकि कभी तो वे किसान समर्थक नजर आते हैं, तो कभी किसान विरोधी, कभी धर्मनिरपेक्ष दिखायी पड़ते हैं, तो कभी सांप्रदायिक। यही नहीं, सोने में सुहागा यह है कि उनकी तस्वीर गरीब नेता के रूप में भी उभरी है। इसलिए अधिसंख्य आवादी यह मानती है कि यदि उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुना गया, तो वे एक बहुत ही कमजोर सरकार का गठन करेंगे जिसे चंद्र शेखर, अजीत सिंह, देवीलाल और बीजू पटनायक जैसे लोग अंदर-ही-अंदर खोखला करेंगे। बात सही भी है, उपर्युक्त लगभग सभी नेता आये दिन एक दूसरे से टकराते रहते हैं तथा कई-कई दिन एक दूसरे से बात नहीं करते। जाहिर है, जिस विपक्ष या जिस नेता के साथ ऐसे लोगों की भीड़ हो, जो आपस में ही तालमेल न बिठा पाते हों, वे कल सत्तारुढ़ होकर क्या गुल खिलायेंगे, उसे समझ पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।

> **यदि वीपी सिंह ने अभी भी अपने दल को मजबूत करने का प्रयास नहीं शुरू किया, तो जनता के समक्ष कांग्रेस-इ के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। नतीजतन अगले चुनाव में बेमन से ही सही, जनता एक बार फिर कांग्रेस को केंद्र की बागडोर सौंपने पर मजबूर हो जायेगी और विपक्ष कई सालों के लिए अंधेरी कोठरी में कैद हो जायेगा।**

कांग्रेस का संकल्प : वीपी सिंह और विपक्ष की इसी कमजोरी से खेलने का कांग्रेस ने संकल्प किया। कांग्रेस को पहला मौका मिला कर्नाटक में। बस फिर क्या था? आनन-फानन विपक्षी सरकार को कमजोर दिखाकर कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कांग्रेस के इस खेल से जहां विपक्ष की छवि धूलधूसरित हुई, वहीं विपक्ष का दम भरनेवालों का मनोबल भी गिरा। हालांकि कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसे लेकर विपक्ष ने काफी हो-हल्ला मचाया, किंतु राज्यपाल वेंकटसुबैया एवं केंद्र ने कितनी होशियारी से संविधान को तोड़-मरोड़ कर कर्नाटक में तख्ता पलटा उसे देश की आम जनता समझने के लिए उत्सुक, नहीं। फिर आम धारणा भी तो वही है कि राजनीति एक गंदा खेल है। यदि कोई हद से बाहर गंदगी फैलाता है, तो उसमें गलत क्या है? मजे की बात यह है कि कर्नाटक के हादसे पर जनता की राय कुछ विपरीत ही नजर आयी, क्योंकि उसने यह माना कि बोम्मई सरकार गिरने का कारण कांग्रेस की गंदी राजनीति नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं का आपसी मतभेद तथा बगल में छुरी मुंह में राम वाली नीति रही। फिर कर्नाटक में जो कुछ हुआ वह भारतीय इतिहास में पहली बार नहीं घटा। आज से दस वर्ष पूर्व १९७९ में भी अपने ही लोगों की कारगुजारियों के कारण एक और जनता सरकार को धूल चाटनी पड़ी थी। आज जो लोग जनता दल के नाम पर एकत्र हुए हैं, वे कमोबेश वही पुराने लोग हैं, बल्कि कुछ नये तथा अत्यधिक आकांक्षी चेहरे भी इस जमावड़े में शामिल हो गये हैं। जाहिर है, जो लोग १९७९ में अपने ही लोगों की पीठ में छुरा भोंकने की कला में माहिर हो चुके हैं, अब वे कला रखते हुए भी खामोश कैसे रह सकते हैं? फिर सबकी अलग-अलग आकांक्षा है, सबका अलग उद्देश्य। तालमेल के अभाव में नामनिहाद एकता के सिवा और क्या हासिल हो सकता है? क्या संयुक्त विपक्ष के नेता इस बात से बाखबर नहीं हैं कि जनता उनकी इस आदत से खूब वाकिफ है? सोचा गया था कि '७९ में जो कुछ हुआ उसकी परिणति को मद्देनजर रखते हुए इस बार विपक्ष मजबूत तालमेल बनायेगा, किंतु ऐसा कुछ दिखायी नहीं पड़ता। सवाल यह है कि जब बंगलौर में आपसी मतभेद बढ़ रहा था तथा कर्नाटक की विपक्षी सरकार पर खतरा मंडराने लगा था उस समय वीपी सिंह (जो विपक्ष के अग्रणी हैं) कहां थे? कौन नहीं जानता था कि केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह बंगलौर में ज्यादा समय देकर बोम्मई के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करा रहे थे? दिल्ली में तो आम चर्चा थी कि बूटा सिंह अपने बंगलौर दौरों के दौरान देवगौड़ा तथा सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करके किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे। किंतु ताज्जुब इस बात पर है कि सब कुछ जानते-बूझते भी किसी विपक्षी नेता ने बंगलौर जाकर स्थिति को संभालने की ज़हमत नहीं की। सचाई तो यह है कि जिस दिन बोम्मई सरकार को बर्खास्त किया गया उस दिन संयुक्त विपक्ष के माननीय नेतागण राष्ट्रीय मोर्चे का घोषणा-पत्र तैयार करने में व्यस्त थे। उनमें से बहुतेरों को तो यह

पता भी नहीं था कि कर्नाटक में उनकी सरकार की किस तरह छीछालेदर हो रही है।

मजबूत केंद्र जरूरी : उपर्युक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए यह कहना गलत न होगा कि भारतीय मतदाता किसी हद तक अक्षमता, भ्रष्टाचार और हिंसा से तो समझौता कर सकता है, किंतु दोबारा दिल्ली में 'खिचड़ी सरकार' बिठाना बेहतर नहीं समझेगा। संभव है, राज्यों में मतदाता 'खिचड़ी सरकार' को मौका दें, क्योंकि वे भलीभांति जानते हैं कि उस पर असली हुकूमत राज्य सरकार की नहीं, अपितु केंद्र की होती है। यही वजह है कि बंबई की सड़कों पर घूमने-फिरनेवाला मतदाता इस बात की परवाह नहीं करता कि शरद पवार या उनकी सरकार का क्या हो रहा है? क्योंकि वह इस तथ्य से खूब वाकिफ है कि उसके भविष्य का संबंध पवार या अंतुले से नहीं। देश की जनता जानती है कि एक कमजोर केंद्र का सीधा मतलब होता है—अस्थिरता और अव्यवस्था—जिसका खमियाजा जनता को भुगतना होता है। क्योंकि देश का विकास तथा जनता का उद्धार केंद्र की कारगुजारियों पर ही निर्भर है। केंद्र किस तरह से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करता है, किस तरह से 'कर' लगाता है तथा कैसी योजनाएं बनाता है, इसी पर देश का मुस्तकबिल आश्रित है। फिर यदि राज्यों में कमजोर सरकारें बनती हैं, तो उनसे जनता को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा ही है। क्योंकि कमजोर राज्य सरकार का अंत राष्ट्रपति शासन को दावत देता है, जिसे आम आदमी चुनी हुई सरकार से बेहतर समझता है। इस बारे में तमिलनाडु की जनता की धारणा उल्लेखनीय है जो आज भी इस बात को दोहराती नहीं थकती कि एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद और करुणानिधि के सत्तासीन न होने से पूर्व का काल कई मायनों में बहुत बेहतर था।

शायद इसीलिए कांग्रेस-इ की चुनावी मुहिम तैयार करनेवालों ने कांग्रेस की स्थिति को बेहतर जताने के लिए विपक्ष की वस्तुस्थिति जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। असल में कांग्रेस जनता को सिर्फ यह बताना चाहती है कि जनता शासन इतना कमजोर है कि उससे बेहतरी की उम्मीद रखना अपने आपको धोखा देना है। अभी तो इस विज्ञापन के लिए कांग्रेस ने सिर्फ कर्नाटक में नक्शा बदला है। चुनाव निकट आते-आते ऐसे अनगिनत सवाल जनता के समक्ष रखे जायेंगे, जिनका जवाब दहला देनेवाला होगा। कांग्रेसी जनता से पूछेंगे कि क्या वीपी सिंह जैसे नेता चंद्रशेखर, हेगड़े, देवीलाल और अजीत सिंह जैसे नेताओं के साथ सरकार बना सकेंगे या बना भी लेंगे, तो क्या सरकार स्थायी होगी?

कांग्रेस की इस मुहिम का उसे फायदा पहुंचेगा। १९७९ की याद देश की जनता को फैसला करने से पहले सोचने पर मजबूर करेगी। फिर जब से विपक्षी एकता के प्रयास शुरू हुए तब से आज तक के विपक्षी इतिहास का जायजा लिया जायेगा, जिसमें आपसी मतभेद, ईर्ष्या और अपना उल्लू सीधा करने की नेताओं की कोशिश भरी पड़ी है। नतीजतन विपक्ष के प्रति जनता की सहानुभूति घटेगी। ऐसे में अफसोस होना लाजिम है। देश का विपक्ष तथा उसके अग्रणी वीपी सिंह कांग्रेस द्वारा उठाये जानेवाले सवालों के जवाब की तैयारी नहीं कर सके हैं, न ही वे इस ओर ध्यान दे रहे हैं। विपक्ष का ज्यादा समय तो ठक्कर रिपोर्ट जैसे मामूली मसलों को उछालने में बीत रहा है। हरियाणा में फिलहाल जनता तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ इसलिए जिंदा है, क्योंकि सरकार में जनता दल के नेताओं को महत्व मिला हुआ है। यदि हरियाणा में भाजपा तालमेल से मुंह मोड़ ले, तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। बेहतर तो यह होगा कि हरियाणा सरकार को जनता दल-भाजपा सरकार न कहकर लोकदल-भाजपा सरकार कहा जाये।

छिनती लोकप्रियता : बहरहाल, विपक्ष तथा वीपी सिंह की जो स्थिति है, वह किसी से ढंकी-छिपी नहीं तथा कांग्रेस-इ की जो स्थिति है वह भी पोशीदा नहीं। कांग्रेस-इ ने अपने संकट को समय रहते जानने की कोशिश की है तथा अपनी स्थिति सुधारने के प्रयास शुरू कर दिये हैं, जबकि विपक्ष आज भी छोटे-छोटे गैरजरूरी मसलों को उछालकर जहां अपना समय नष्ट कर रहा है, वहीं जनसमर्थन भी खो रहा है। यहां पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि भारत में सिर्फ दो ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आज भी घटकों में नहीं बंटे हैं। इनमें से एक कांग्रेस है, दूसरी भाजपा। इनके अतिरिक्त सभी दल छोटे-छोटे गुटों में बंट चुके हैं। मिसाल के तौर पर दो जनता पार्टी हैं, तीन या चार कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। यही नहीं, अकालीदल तो आधा दर्जन गुटों में बंट चुका है और लोकदल के कितने हिस्से हो चुके हैं तथा अभी और कितने होंगे, यह बता पाना असंभव है।

ऐसे में वीपी सिंह के लिए अपनी स्थिति सुधारना बहुत जरूरी है। अपनी स्थिति सुधारने से भी ज्यादा जरूरी अपनी पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए विपक्ष को हौवा नहीं माना जा सकता। जब तक जनता दल मजबूत नहीं होता, मजबूत विपक्ष की बात करना सिरे से बेमानी होगा। यदि वीपी सिंह ने अभी भी अपने दल को मजबूत करने का प्रयास नहीं शुरू किया, तो जनता के समक्ष कांग्रेस-इ के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। नतीजतन अगले चुनाव में बेमन से ही सही, जनता एक बार फिर कांग्रेस को केंद्र की बागडोर सौंपने पर मजबूर हो जायेगी और विपक्ष कई सालों के लिए अंधेरी कोठरी में कैद हो जायेगा। ◆

अनेक मॉडल! आकर्षक रंग!

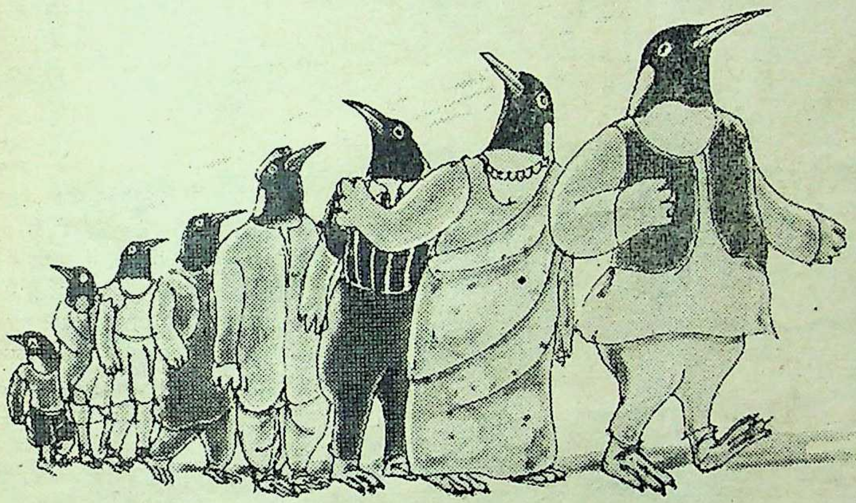

विभिन्न साइज़ों के शानदार मॉडल। आप के चयन के लिए अनुपम आकर्षक रंगों में। इतने विभिन्न मॉडल मुश्किल से ही उपलब्ध हैं तथा केवल केल्विनेटर ही प्रस्तुत करते हैं। आपके चयन के लिए, आपकी आवश्यकतानुसार, आपकी पसन्द के अनुकूल। परन्तु उन सब में एक सामान्य गुण है विख्यात केल्विनेटर की कार्यकुशलता का प्रतीक — 'पावर-सेवर' कॅम्प्रेसर। यह शीघ्र ठंडा करता है तथा उससे शीघ्र बर्फ़ बनाता है। चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो। यह न्यूनतम बिजली की खपत करके अपनी ख्याति की कसौटी पर खरा उतरता है। तथा वोल्टेज का कितना भी उतार चढ़ाव इसके कुशल कार्य में विघ्न नहीं डाल सकता।

आप इसमें वस्तुएं रखने की विशाल क्षमता से चकित रह जाएंगे। क्योंकि इसके कोने-किनारे रहित विशिष्ट अन्दरूनी डिज़ाइन में, अधिकतम स्थान का उपयोग हो सकता है। सुदृढ़, सम्पूर्ण-स्टील निर्माण तथा मज़बूत ए बी ऐस लाइनर इसके अन्दरूनी एवं बाहरी भाग को अधिक मज़बूती तथा टिकाऊपन प्रदान करते हैं।

इसलिए इसकी विशाल श्रृंखला के कारण, केल्विनेटर का ही चयन कीजिए।

Mutual 4711 Gd HN

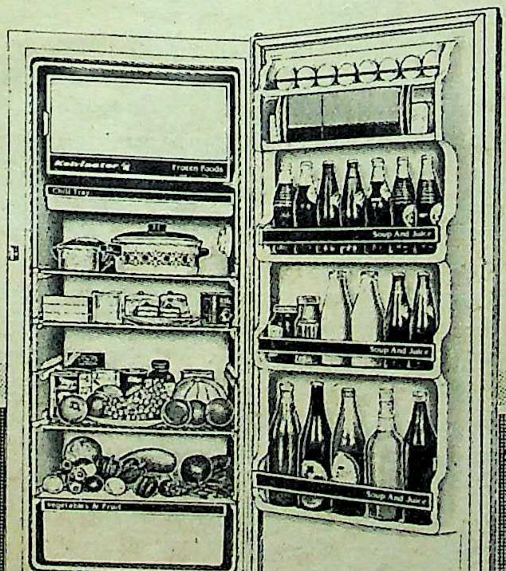

Kelvinator
Frozen Foods
Chill Tray
Soup And Juice
Vegetables & Fruit

286 लीटर तथा 165 लीटर मॉडल
डी.जी.एस. एण्ड डी रेट कन्ट्रैक्ट
पर भी उपलब्ध!

विक्रय एवं सर्विस के लिए

एक्सपो मशीनरी लिमिटेड
प्रगति टॉवर, 26, राजिन्द्रा प्लेस,
नई दिल्ली-110 008.

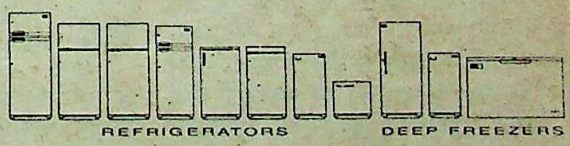

REFRIGERATORS
DEEP FREEZERS

केल्विनेटर

रेफ्रिजरेटर

"इसकी ठण्डक...बेमिसाल!"

वेस्टइंडीज दौरा

भारत की छीछालेदर का उत्तरदायी कौन ?

पराजय दुखद एवं कटु होती है। भ्रमणकारी भारतीय क्रिकेट टीम की सीमित ओवर 'मिनी टेस्ट' (एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र) और टेस्ट शृंखला में करारी हार से जहां भारतीय क्रिकेट जगत हतप्रभ है, वहीं क्रिकेट के दीवाने कैरेबियन दर्शकों में भी निराशा की लहर चल रही है। एक दिवसीय और टेस्ट मैचों की शृंखलाओं में संघर्ष नाम मात्र भी नही था। प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण दौरा नीरस रहा। शृंखला के समापन पर लगा मानो भारतीय क्रिकेट भड़भडाकर चारों खाने चित्त हो गयी। एक कैरेबियन समीक्षक की टिप्पणी रही, "यह मुकाबला हाथी और चींटी के बीच का-सा लगा।"

दरअसल, वेस्टइंडीज में भारतीय टीम की पराजय नहीं, बल्कि उसकी छीछालेदर हुई है। भ्रमणकारी दल छिन्न-भिन्न हो गया है। भारतीय क्रिकेट की ऐसी दुर्दशा हाल के वर्षों में तो देखने को नहीं मिली। कैरेबियन में इस शोचनीय प्रदर्शन को लेकर चर्चा का बाजार गरम है। हर गली-कूचे, काफी हाउस, और-तो-और संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसद भी टीवी सीरियल 'ये है वह जिंदगी' के अंदाज में पूछ रहे हैं, "भई, क्या हो रहा है वेंगसरकर ?"

भारतीय टीम के निम्नस्तरीय प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि खिलाड़ी इस भागमभाग दौरे पर विभिन्न व विषम परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार अपने आपको ढाल नहीं पाये। अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी के आंतरिक एवं बाहरी वातावरण के बीच तालमेल आवश्यक है। छोटे दौरे पर यह तालमेल कायम होने में समय लगता है। उधर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने (कैरेबियन पहुंचते ही पराजयों का सामना) के कारण टीम सटपटा गयी और दिशा व मार्ग खो बैठी।

विख्यात खेल समीक्षक डिकी रत्नागर का मत है कि इतने छोटे दौरे के लिए १७ खिलाड़ियों का चयन कुछ खिलाड़ियों को सैर-सपाटा करवाना मात्र ही हो सकता है। रत्नागर का कथन सही सिद्ध हुआ, क्योंकि आफस्पिनर वेंकटरमण, अतिरिक्त विकेटकीपर सबा करीम और मध्यम तेज गेंदबाज संजीव शर्मा अधिकतर दौरे पर पैवेलियन और होटल में ही समय गुजारते रहे।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, यह है कि जब भी वेस्टइंडीज टीम किसी से भी हारी है, तो अगले मुकाबले में घायल शेर की तरह वह अपने प्रतिद्वंद्वियों पर टूटी है। पिछली १९८७-८८ की शृंखला में मद्रास टेस्ट में वेस्टइंडीज टीम पारी से पराजित हुई थी और उस ऐतिहासिक विजय के कर्णधार थे, लेग-स्पिनर नरेंद्र हिरवानी। १९८३ में अपना विश्व विजेता का खिताब खोने के बाद, क्रुद्ध वेस्टइंडीज टीम ने विश्वविजेता भारत को १९८३ में एक दिवसीय शृंखला में ५-० और टेस्ट में ३-० से चित कर दिया था। इस बार भी कैरेबियन क्रिकेटर मद्रास की हार का बदला चुकाने की ताक में थे। इस प्रतिशोधी दृष्टिकोण के कारण ही घरेलू टीम ने मेहमान टीम को बुरी तरह रौंद डाला।

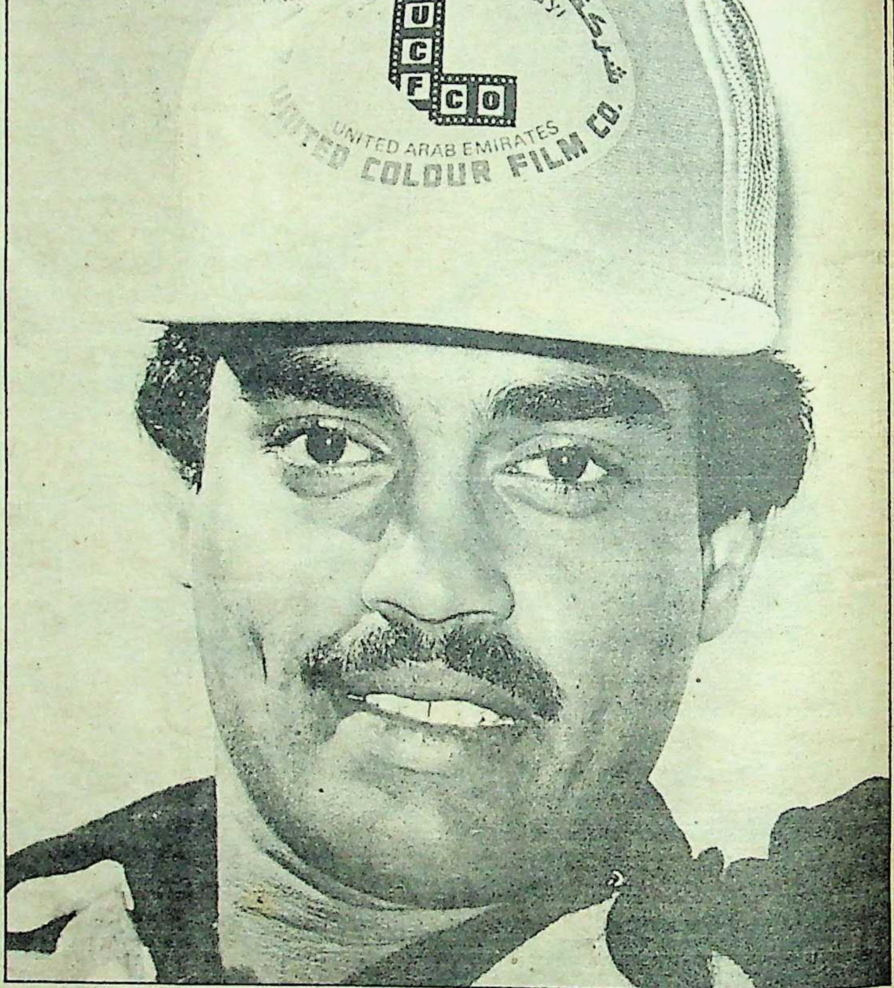

असफल कप्तानी : वेंगसरकर

शृंखला का यदि सही मूल्यांकन किया जाये, तो यह कहना अनुचित न होगा कि वेस्टइंडीज टीम ने भारतीयों की एक भी न चलने दी। हमारी हर चाल का जवाब उनके पास था, जबकि उनके रामबाणों को झेलने में भारतीय टीम असमर्थ रही। यही भारत की पराजय का मुख्य कारण बना।

क्रिकेट समीक्षक और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्वकप्तान टोनी लुइस ने भारतीय टीम के शोचनीय प्रदर्शन के बारे में लिखा है : 'बल्लेबाज प्रायः गेंद की लाइन में आकर और शरीर को उसके पीछे लाकर नहीं खेले। बहुत ही कम स्ट्रोक सीधे खेले गये। स्वाभाविक है, अधिकतर कैच स्लिप या विकेट कीपर के पास गये।

इसी प्रकार भारतीय गेंदबाजी को भी लुइस ने टेस्ट स्तरीय नहीं आंका है। वे लिखते हैं: 'कपिलदेव २५ टेस्ट के बाद और १९८५-८६ के

एडीलेड टेस्ट के पश्चात त्रिनिदाद में केवल पांच विकेट लेने में सफल रहे।' इससे साफ संकेत मिलता है कि भारतीय गेंदबाजी में पैनेपन का अभाव था जिसका भरपूर लाभ वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने उठाया।

भारत की असफलता की कालिख बहुत कुछ उद्घाटक बल्लेबाजों पर पोती जा सकती है। सलामी बल्लेबाज श्रृंखला में भारत को अर्धशतकीय आरंभ तक न दे पाये। उनके जल्दी आउट होने से शेष बल्लेबाजी क्रम पर मनोवैज्ञानिक दबाव अत्यधिक बढ़ गया।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक बल्लेबाज एक स्वाभाविक क्रम पर खेलना चाहता है। उस स्थान पर खेलने के लिए उसकी मनःस्थिति ऐसी बन जाती है कि वह सभी परिस्थितियो के लिए कटिबद्ध रहता है। नवजोत सिंह सिद्धू स्वाभाविक 'ओपनर' नहीं हैं। उनसे पारी आरंभ करा कर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वे स्वाभाविक 'स्ट्रोक-प्लेयर' हैं, परंतु आरंभिक दबाव ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया जिससे उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। यही हाल रवि शास्त्री का भी हुआ है। तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी उन्हें रास नहीं आ रही है, यद्यपि बारबेडोस टेस्ट में उन्होंने शतकीय पारी अवश्य खेली थी। शास्त्री के लिए पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करना ही उपयोगी हो सकता है। श्रीकांत की ही तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन की अस्वस्थता और उनके कई बार रन आउट होने का दंड भ्रमणकारी दल के लिए बहुत महंगा पड़ा।

वेस्टइंडीज भ्रमण से पूर्व कंप्यूटर के अनुसार दिलीप वेंगसरकर विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाज आंके गये थे, परंतु आज वही बल्लेबाज धूल चाट रहा है। भारतीय टीम को अपने प्रमुख बल्लेबाज से निरंतर बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा थी। उनकी पारियां भारतीय टीम के अच्छे स्कोर के लिए आधार स्तंभ बन सकती थीं। त्रिनिदाद (दूसरी पारी) के अलावा वेंगसरकर को अपने बल्ले से करिश्मे दिखाने के अधिक अवसर प्राप्त नहीं हो पाये। वेस्ट इंडीज के तेजतर्रार गेंदबाज ईयन बिशप, कोर्टनी वाल्श, कर्टली एंबरोस और मैल्कम मार्शल पटकी गेंदों और आफ स्टंप पर अपना आक्रमण केंद्रित करके बराबर भारतीय बल्लेबाजो को छकाते रहे। इस श्रृंखला में आफ स्टंप परीक्षा की कसौटी रही, जिस पर भारतीय बल्लेबाज खरे नहीं उतरे।

दौरे पर प्रदर्शन के विश्लेषण से साफ है कि वेंगसरकर, अजहरुद्दीन, शास्त्री, कपिल, अरुण लाल, सिद्धू, मोरे, अयूब आदि के खेल-कौशल में तीस चालीस रन बनाने के बाद एकाग्रता का अभाव लगा। उसी प्रकार गेंदबाज थोड़ी बहुत सफलता अर्जित करने के बाद ढीले पड़ जाते थे। वे जानते थे कि अब पसीना बहाने का भला क्या फायदा? अगले टेस्ट में तो हमारा स्थान सुरक्षित है ही। लगता है, भारतीय बल्लेबाजों को रन बटोरने की भूख सताती ही नहीं। इससे सारे दौरे में भारतीय टीम का प्रदर्शन बराबर उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा। इसके लिए बहुत कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को दोषी ठहराया जा सकता है। उनका टीम के लिए योगदान न के बराबर रहा जो अंत में भारत के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ।

पिछले कई वर्षों से भारतीय गेंदबाजी का स्तर बराबर गिरता जा रहा है। एक दिवसीय श्रृंखला में किसी हद तक केवल कपिलदेव ही रन रफ्तार पर अंकुश लगाने में सफल रहे। उधर अयूब एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने टेस्ट में नपी-तुली गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाजों को थोड़ा-बहुत बांध कर भी रखा। परंतु लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी अपना चमत्कारी प्रदर्शन दुहरा न सके जो भारत को काफी महंगा पड़ा।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि त्रिनिदाद टेस्ट की दूसरी पारी में कपिल और चेतन शर्मा ने प्रभावशाली गेंदबाजी की। यदि इसी लय और लगाव के साथ अन्य मैचों में गेंद-प्रदर्शन होता, तो भारत की मुसीबतें कुछ कम हो सकती थीं।

परंतु गेंदबाजी को दिशाहीन व नाकारा करने में क्षेत्र रक्षकों का बड़ा हाथ रहा है। वेस्टइंडीज के नामी बल्लेबाजों गोर्डन, ग्रीनिज, डेसमंड हेंस, रिची रिचर्ड्सन, गस लोगी, जैफरी डूजों और कीथ आर्थरटन को कई जीवनदान प्राप्त हुए और उन्होंने बहती गंगा में जमकर हाथ धोये।

कप्तान वेंगसरकर अपने आक्रमण का उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाये। उन्हें कई बार पता नहीं चलता था कि कौन-सा बाण कहां उपयोग में लाया जाये। और-तो-और, उनकी व्यूहरचना भी विवादास्पद रही। जब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, तो उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और आक्रामक मोड़ पर वे फूंक-फूंक कर कदम रखते थे। विकेट कीपर किरण मोरे ने जहां कुछ साहसी पारियां खेलीं, वहीं उनका विकेट रक्षण स्तरीय नहीं रहा। खेल पट्टियों की असमतल उछाल ने मोरे के लिए काफी परेशानियां पेश कीं।

इस दौरे में भी अंम्पायरों का निर्णय कई बार विवाद की चपेट में आया। भारतीय टीम ने तो खुलकर विरोध किया। अब तो हर दौर में ऐसा आरोप लगने लगा है और उसी के साथ तटस्थ अंपायरों की मांग का जोर भी पकडता है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज ने तो पहले से ही तटस्थ अंपायरों के मामले को आगे बढ़ाया है। हाल में न्यूजीलैंड ने भी इस मांग का समर्थन किया है। एक बात तो साफ है कि तटस्थ अंपायरों की नियुक्ति से संभवतः अंपायरों पर उंगली उठना बंद हो सकता है।

—रवि चतुर्वेदी

मुंह ताकते रह गये: कपिल और वेंगसरकर

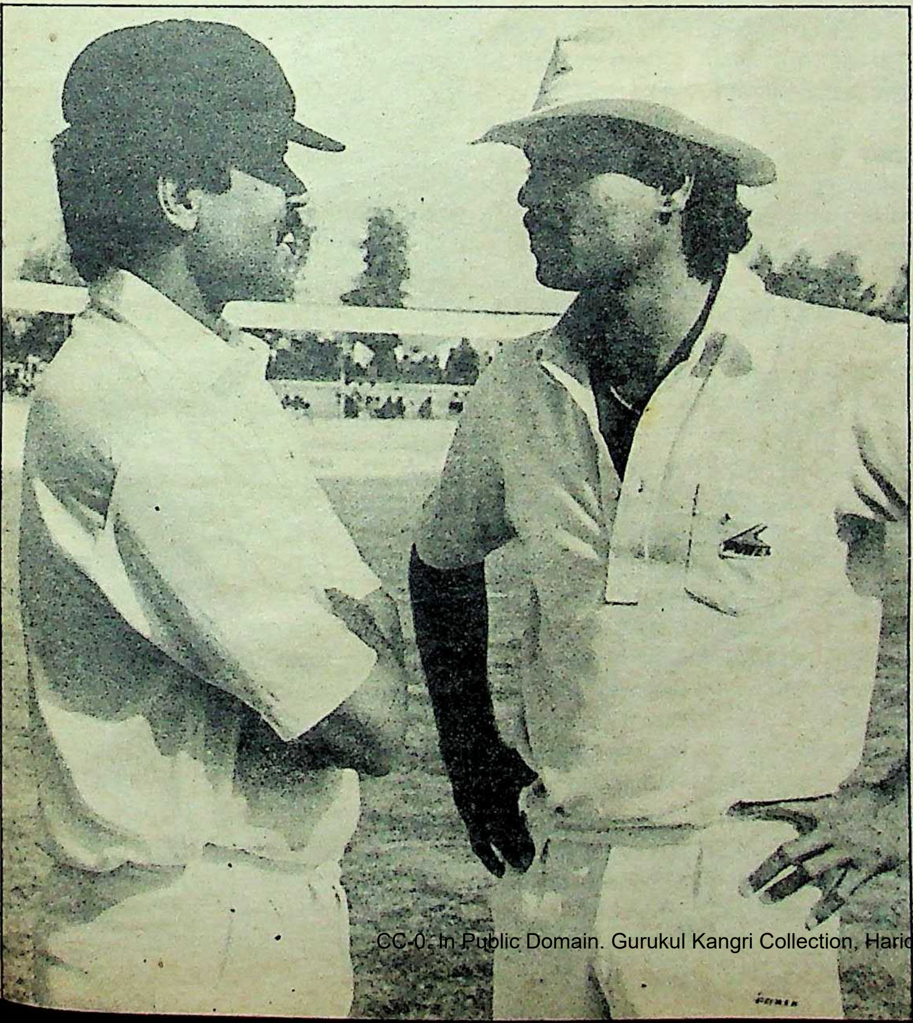

साढ़े पांच खरब रुपए का मनमाना खर्च

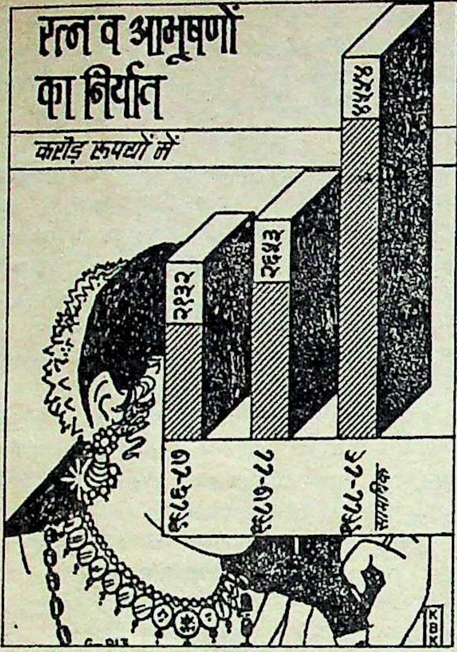

संभवतः लोकतंत्र के जन्म लेने का मूल कारण यह भी था कि सामंत जनता पर मनमाने कर लगाता था और सरकारी खजाने में जमा जनता के धन का मनमर्जी से उपयोग करता था। कुछ ऐसा ही वाकया भारतीय संसद में भी हो रहा है। लोकसभा में २६ अप्रैल, १९८९ को बिना किसी बहस के विभिन्न मंत्रालयों ने चालू वित्त वर्ष के लिए ५ खरब, ४३ अरब, ६८ करोड़ रुपए के खर्चे की मंजूरी ले ली। भारत के स्थायी कोष के मनमाने खर्चे का यह अकेला उदाहरण नहीं है। १९८३ में भी एक झटके में एक खरब रुपए की मांगों को बिना बहस के मंजूर कर लिया गया था। इसी प्रकार, १९८७ में भी राजीव सरकार ने बिना बहस के दो खरब रुपए के खर्चों की मंजूरी खुद ही ले ली थी। स्पष्ट है, सरकारी खजाने से खर्च होनेवाले जनता के धन पर जनता के प्रतिनिधियों के अंकुश का महत्व खतम होता जा रहा है।

भारत के सांसद, मंत्रियों और लोकसभा व राज्यसभा के कामकाज पर एक आकलन के अनुसार करीब एक हजार रुपए प्रति सेकेंड खर्च होते हैं और सांसदों के वेतन भत्ते दस हजार रुपए प्रतिमास तक पहुंच गये हैं। लेकिन यह रोचक तथ्य है कि भारतीय संसद में किसी भी साल ३६५ दिनों में से १५५ दिनों से अधिक कामकाज नहीं हुआ। १९५३ व ५४ में लोकसभा का सत्र क्रमशः १३७ दिनों, १९५६ में १५१ और पंडित नेहरू के अंतिम वर्ष १९६३ में १२२ तथा १९६६ में ११९ दिनों तक चला। १९७५ में तो लोकसभा सिर्फ ६३ दिन तक चली थी। गत वर्ष १९८८ में ही लोकसभा में सिर्फ १०२ दिनों तक कामकाज हुआ।

१९८८ में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अंतरराष्ट्रीय हाकी के लिए अब कुछ नये नियम बना दिये गये हैं—इसके अनुसार अब कोई खिलाड़ी गेंद को उछालकर लंबी दूरी का पास नहीं दे सकेगा। इसके कारण गेंद अधिकांश समय या तो हवा में रहती थी या मैदान के बाहर। अब इसी प्रकार गोलरक्षक का पैनाल्टी कार्नर रोकने के लिए मैदान में लेट जाना नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस नियम परिवर्तन से छोटे-छोटे पास देकर नफासत से खेलने के आदी भारतीय खिलाड़ी फायदे में रहेंगे।

भारतीय दूरदर्शन ने १९८८ में विज्ञापनों के जरिए एक अरब ५२ करोड़ ४१ लाख रुपए कमाये, जबकि इस वर्ष सिर्फ तीन महीनों में (जनवरी-मार्च) ही विज्ञापनों से उसे ४४ करोड़ ४२ लाख रुपए की आय हो चुकी है।

देश के छह राज्यों (गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल व पंजाब) और केंद्र शासित सभी इलाकों (चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, तथा पांडीचेरी) ने दावा किया है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के हर गांव में घर-घर तक बिजली पहुंचा दी है।

पूरे देश में बीमार औद्योगिक इकाइयों की संख्या एक लाख, ५९ हजार २८३ हो गयी है।

पूरे देश में १९८८-८९ वित्त वर्ष में १५२६८८ ट्रक, कार, स्कूटर और मोटर साइकिलों का उत्पादन हुआ। जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या ११,४२,४३१ थी। अर्थात १९८७-८८ के मुकाबले १९८८-८९ में मोटरचालित वाहनों के उत्पादन में ९ लाख ८९ हजार ७४३ वाहनों की कमी आयी है।

यौन परिवर्तन कराकर पुरुष बनी विश्व की प्रथम अमरीकी महिला क्रिस्टीन जर्गेन्सन का इसी तीन मई को ६२ वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। ३० मई, १९२७ को जन्मी जर्गेन्सन ने १९५२ में डेनमार्क में यौन परिवर्तन कराया था। पुरुष बन जाने के बावजूद उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन वह इतनी चर्चित हुई और उसे उपहार में इतना धन व आभूषण मिले कि उसकी जिंदगी आराम से गुजर गयी।

फ्रांस की सरकार ने इस वर्ष कुछ ऐसे तथ्य प्रसारित किये हैं जो फ्रांस राज्यक्रांति से संबंधित कई गलत धारणाओं को दूर करते हैं। यह माना जाता रहा है कि क्रांतिकारियों ने बास्टिल जेल पर हमला करके हजारों कैदियों को मुक्त कराया तथा गिलोटिन (सिर काटने का एक यंत्र) के जरिए फ्रांस के उच्च वर्ग के लोगों के सिर काटे गये थे, जबकि नये तथ्यों के अनुसार उस समय बास्टिल जेल में हजारों नहीं सिर्फ सात कैदी थे और गिलोटिन से मारे गये सभी लोगों में से सिर्फ दस प्रतिशत उच्च वर्ग के थे। इसी प्रकार यह भी सही नहीं है कि सिर्फ गिलोटिन के जरिए ही लोगों को मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस की राज्यक्रांति के दौरान मारे गये ४ लाख लोगों में से अधिकांश गोली व आग से मारे गये थे। यह भी सही नहीं है कि गिलोटिन से मौत कम तकलीफदेह होती है। इसी प्रकार यह माना जाता है कि फ्रांस की महारानी मेरी एन्टोनिटे ने रोटी मांग रही भूखी भीड़ को केक खाने की सलाह दी थी, जबकि रूसो की पुस्तक कन्फेशन्स में यह पंक्ति किसी अज्ञात राजकुमारी ने कही है और मेरी एन्टोनिटे तो इस पंक्ति के प्रचारित होने के दो साल बाद १७७० में फ्रांस आयी थी।

अमरीका के प्रसिद्ध नगर फिलाडेल्फिया से सौ मील की दूरी पर स्थित १५०० की आबादीवाला गांव सैंट्रेलिया पूरी दुनिया में सबसे गर्म गांव है। यह गांव एक ऐसे कोयला खदान पर बसा हुआ है जो पिछले २५ वर्षों से आग में धधक रहा है, लेकिन इस आग को बुझाने का कोई उपाय अमरीका के पास नहीं है।

वर्ष १९८८ में ८० लाख बेरोजगारों ने रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज कराये—इस प्रकार देश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या तीन करोड़ से अधिक हो गयी है। रोचक तथ्य यह है कि पूरे देश के बेरोजगार दफ्तर सिर्फ एक प्रतिशत बेरोजगारों को ही बमुश्किल काम दिला पाते हैं।

पिछले तीन सालों में हुई १७९३ रेल दुर्घटनाओं में ७२७ लोग मारे गये तथा दो हजार लोग घायल हुए।

इस बार अनुमान है कि खरीफ (१९८८-८९) में ६ करोड़ २७ लाख टन चावल का उत्पादन होगा।

देश में १९८८-८९ में कपड़ा मिलों के बंद होने से एक लाख ८५ हजार श्रमिक व कुशल कारीगर बेकार हो गये हैं।

एक अनुमान के अनुसार हिंद महासागर में एक करोड़ से डेढ़ करोड़ वर्ग किलोमीटर (भारत से १०-१५ गुना बड़े) क्षेत्र में ३५०० से ६००० मीटर गहराई में मैंगनीज, निकल, तांबा तथा कोबाल्ट जैसी धातुओं के अकूत भंडार भरे पड़े हैं, जिनका दोहन करने के लिए भारत के समुद्र विकास विभाग ने एक योजना बनायी है। **—संयोजन : विनोद मिश्र**

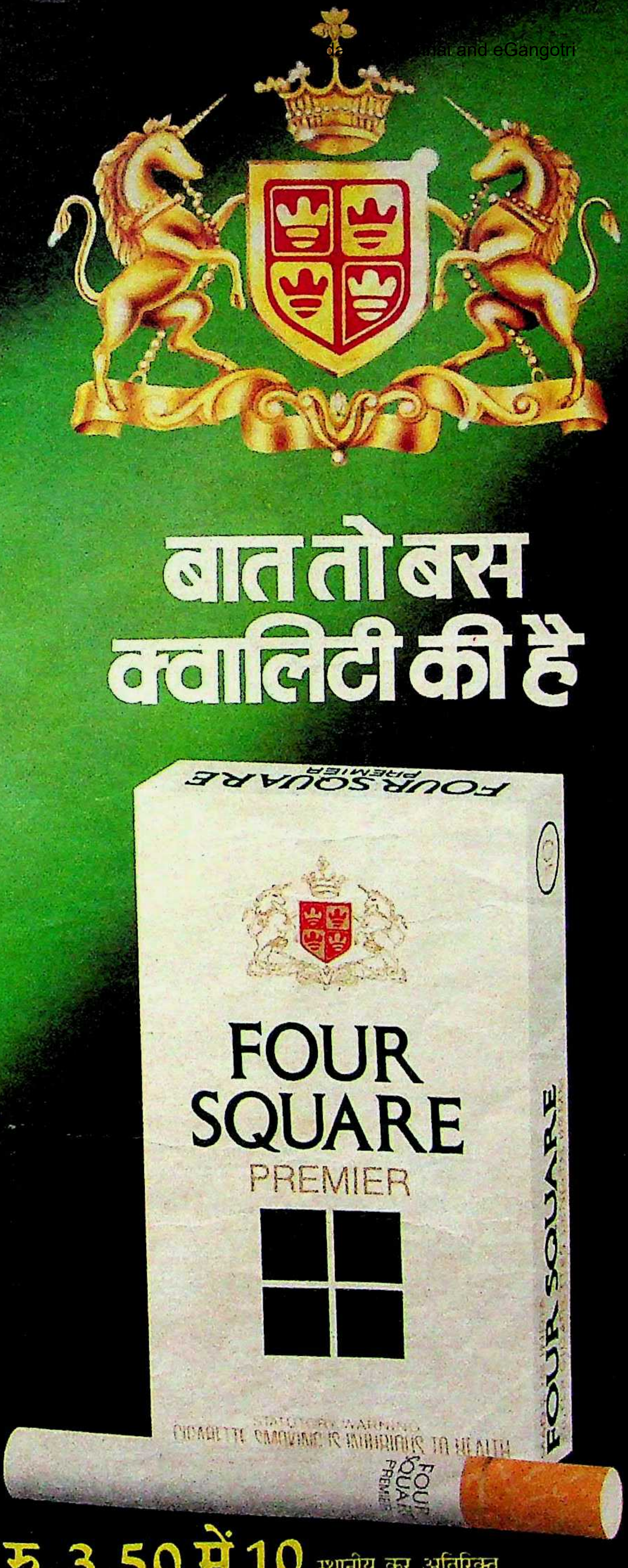
बात तो बस
क्वालिटी की है
FOUR SQUARE
PREMIER
FOUR
SQUARE
PREMIER
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH
FOUR SQUARE
FOUR
SQUARE
PREMIER

रु. 3.50 में 10 स्थानीय कर अतिरिक्त

वैधानिक चेतावनी : सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
STATUTORY WARNING CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

बूटा सिंह की घेरेबंदी

बूटा सिंह को देश के गृहमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए बड़ी लंबी और जटिल यात्रा तय करनी पड़ी है। उनके प्रशंसक उनकी इस उपलब्धि का श्रेय उनकी मेहनत, लगन और अपने नेता के प्रति उनकी अक्षुण्ण निष्ठा को देते हैं, तो उनके आलोचकों का कहना है कि यहां तक वे तिकड़म और जीहुजूरी की बैसाखियों के जरिये पहुंचे हैं। बूटा सिंह राजीव गांधी के विश्वस्त सलाहकार ही नहीं माने जाते, बल्कि उन पर होनेवाले हर वार को भी वे अपने ऊपर लेते रहे हैं। लेकिन अब स्वयं बूटा सिंह सीधे निशाना बन गये हैं। विपक्षी तो विपक्षी, उनकी पार्टी के लोग भी उनके पीछे हाथ धो कर पड़ गये हैं। उन पर गृहमंत्री के पद का पार्टी के लिए दुरुपयोग करने के आरोप तो हैं ही, साथ ही उन पर ताजा आरोप यह लगा है कि उन्होंने अपने पुत्रों के व्यावसायिक हितों के लिए अपने राजनीतिक रुतबे का नाजायज इस्तेमाल किया है। पंजाब के निर्धन हरिजन परिवार में जन्मे, मामूली चपरासी से जिंदगी शुरू करनेवाले देश के सर्वाधिक विवादास्पद गृहमंत्री बूटा सिंह के व्यक्तित्व, राजनीतिक महारत और कांग्रेस-इ में उनकी अहमियत का आकलन :

"उस सरदार और इस सरदार में जमीन-आसमान का फर्क है। एक (सरदार वल्लभ भाई पटेल) ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री के रूप में दर्जनों नरेश शासित राज्यों को एकजुट और सुदृढ़ किया था, तो दूसरे (बूटा सिंह) ने मौजूदा गृहमंत्री के रूप में विपक्ष शासित राज्यों में तख्तापलट करने के साथ ही स्वयं अपनी पार्टी द्वारा शासित अनेक राज्यों में बुलडोजर तकनीक अपना कर वहां के सिपहसालारों की रातों की नींद हराम कर रखी है।" कर्नाटक में ताबड़तोड़ ढंग से राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राजधानी के कनाट प्लेस स्थित काफी हाउस में गरमागरम बहस के दौरान एक बुद्धिजीवी की उक्त टिप्पणी बूटा सिंह के बारे में फैली आमधारणा का प्रतिबिंब है।

जालंधर के निकट मुस्तफापुर गांव के एक गरीब हरिजन परिवार में जन्मे-पले, कम्युनिस्ट पार्टी के पंजाबी मुखपत्र 'फुलवारी' में चपरासी से कैरियर शुरू करने, बरास्ते अकाली दल कांग्रेस में आने, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी और उनके पुत्र-राजीव गांधी—के सबसे विश्वासपात्र और करीबी माने-जाने वाले भारत के तेरहवें (?) गृहमंत्री बूटा सिंह आज जितने बहुचर्चित हैं, उतने ही विवादास्पद भी। तल से शिखर को छूने के कारण उनका व्यक्तित्व जितना प्रेरक और वे जितने प्रशंसा के पात्र हैं, उतने ही मंजिल तक पहुंचने के लिए किये गये कामों और अपनाये गये मार्गों के कारण घृणा और विरोध के भी। विरोध और विवाद गृह मंत्रालय में आने के पश्चात न केवल बढ़ा, बल्कि जैसे-जैसे उनकी पकड़ मजबूत होती गयी, उग्रतम भी होता गया। आज हालात ये हैं कि विपक्ष तो स्वाभाविक शत्रु है ही, उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों और सहयोगियों (केंद्रीय मंत्रियों) की तलवारें भी उनके खिलाफ म्यान के बाहर आ गयीं प्रतीत होती हैं।

भारत के तेरहवें (?)
गृहमंत्री बूटा सिंह आज जितने बहुचर्चित हैं,
उतने ही विवादास्पद भी।
तल से शिखर को छूने के कारण
उनका व्यक्तित्व जितना प्रेरक
और वे जितने प्रशंसा के पात्र हैं,
उतने ही मंजिल तक
पहुंचने के लिए किये गये कामों और
अपनाये गये मार्गों के कारण घृणा और
विरोध के भी।

ताजा विवाद: तलवारें म्यान के बाहर कुछ अर्से से रही हैं। किंतु १९ अप्रैल, १९८९ को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन (रीको) की भिवाड़ी स्थित रुग्ण इकाई आर्यावर्त प्लाइवुड के गृहमंत्री बूटा सिंह के पुत्रों द्वारा किये गये कथित नाजायज सौदे की कथा के प्रकाशन ने बूटा सिंह विरोधियों के हौसले और बुलंद कर दिये हैं। विशेषकर इसलिए कि इस भंडाफोड़ का श्रेय विपक्ष के माथे न जाकर स्वयं कांग्रेसियों—स्पष्टतया गृहमंत्री के जाने-माने साथियों—माखनलाल फोतेदार, बलराम जाखड़ से लेकर वीर बहादुर सिंह, सतीश शर्मा आदि के मत्थे मढ़ा गया है।

दोहरा दायित्व: उल्लेखनीय है कि पक्ष-विपक्ष में सक्रिय बूटा सिंह विरोधी लाबी की शिकायतों की सूची और विरोधियों की कतार लम्बी होती गयी है। नतीजतन बूटा सिंह चौतरफा हमलों से घिरे नजर आने लगे हैं। सामान्यतया आरोप गृह मंत्रालय की शक्ति के दुरुपयोग के रहे हैं, जिनके लिए स्वयं बूटा सिंह को दोषी करार दिया गया है। ऐसी धारणा है कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त मंत्री के नाते उनके जिम्मे एक ओर विपक्ष शासित राज्यों में समस्याएं बढ़ाना, तो दूसरी ओर कांग्रेस शासित प्रदेशों में समस्याओं के समाधान ढूंढ़ना है। इतिहास गवाह है कि दोनों ही क्षेत्रों में गृहमंत्री बूटा सिंह न्यूनाधिक रूप में खरे उतरे हैं। अप्रैल-मई, १९८६ में उनके गृह मंत्रालय संभालने के पश्चात शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सुख-चैन की नींद आयी हो। यह दूजी बात है कि विपक्ष शासित राज्यों पर उनकी विशेष अनुकम्पा रही है।

बूटा सिंह की 'कृपादृष्टि' के वर्तमान केंद्र बिंदु असम के शासक दल असम गण परिषद के सांसद दिनेश गोस्वामी ने 'माया' से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि गृहमंत्री 'विभाजन द्वारा शासन' की प्रथा में विशेष महारत रखते हैं। उनका मानना है कि असम में बोडो आंदोलन को हवा देकर हिंसा भड़काने का काम गृहमंत्री कर रहे हैं। वे कहते हैं, "राज्य सरकार पर समाधान का प्रयास न करने का दोषारोपण सरासर अन्यायपूर्ण है, क्योंकि खमियाजा तो राज्य सरकार ही उठा रही है। हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, पर दार्जिलिंग की घटनाओं और केंद्र के प्रोत्साहन ने आंदोलनकारियों के हौसले और बुलंद किये हैं। आंदोलन को बढ़ावा देने में केंद्रीय अधिकारियों की भूमिका उग्रवादियों से उनके संबंधों-संपर्कों से स्पष्ट हो जाती है। राज्य सरकार को नजरअंदाज कर स्वयं केंद्रीय मंत्री भी उनसे मिलते रहे हैं।" इशारा निश्चित तौर पर गृह राज्य मंत्री संतोष मोहन देव की ओर था। इस पर गृहमंत्री बोले, "झगड़ा स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का है, गृह मंत्रालय का इससे कुछ लेना-देना नहीं। हम तो बराबर उन्हें हर संभव सहायता दे रहे हैं।"

सहायता मात्र दिखावे की है, ऐसा असमियों

विश्वस्त सलाहकार: राजीव गांधी और बूटा सिंह

का मानना है। दिनेश गोस्वामी के अनुसार केंद्र, विशेषकर गृहमंत्री की राजनीति और रणनीति यही है कि अगले चुनाव तक समस्या को येन-केन-प्रकारेण बनाये रखा जाये। चुनाव के ऐन पूर्व हस्तक्षेप कर ऐलान किया जाये कि राज्य में शांति मात्र कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है। यह सत्तादल असम गण परिषद के बस का रोग नहीं। फिर त्रिपुरा जैसी स्थिति पैदा कर एक ओर चुनाव जीत लें, दूसरी ओर, अपने द्वारा पोषित उग्रवादियों से समझौता कर विजय पताका फहरायें।

असम में त्रिपुरा का इतिहास दोहराया जायेगा अथवा हाल का कर्नाटक प्रकरण, यह प्रश्न आज न सिर्फ सभी विपक्षी पार्टियों, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखनेवालों के लिए सर्वोपरि महत्व का बन गया है। यद्यपि न केवल गृहमंत्री, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री ने बार-बार दोहराया है कि कर्नाटक सरकार गिराने में केंद्र अथवा कांग्रेस ने कोई भूमिका नहीं निभायी।

कर्नाटक का किला फतह करने की रणनीति बनाने और उसे कुशलतापूर्वक लागू करनेवाले कोई अन्य नहीं, गृहमंत्री बूटा सिंह ही हैं। यद्यपि गृहमंत्री इस बात से इनकार करते हैं कि इसमें उनकी कोई भूमिका थी। किंतु पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने न सिर्फ उन पर सीधे-सीधे विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाये हैं, बल्कि उसके सबूत पेश करने का भी दावा किया है। प्रेक्षकों का कहना है कि गृहमंत्री बूटा सिंह इस मुहिम में लगभग एक वर्ष पूर्व तब से जुटे रहे हैं, जब राम जेठमलानी को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेगड़े द्वारा राज्यसभा टिकट दिये जाने के मुद्दे पर जनता पार्टी में देवगौड़ा की अगुवाई में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गयी थी। उस समय मौके का भरपूर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तुरत-फुरत बंगलौर पधारनेवाले कोई अन्य नहीं, स्वयं बूटा सिंह थे। यही नहीं, गैरइंका शासित राज्यों में बिना मुख्यमंत्रियों से सलाह-मशविरा किये राज्यपालों की तैनाती की सूचना टेलीफोन से देने के विवाद में फंसे गृहमंत्री ने कर्नाटक में पी वेंकटसुबैया की नियुक्ति वहां जनता पार्टी में बढ़ती खायी का लाभ उठाने के लिए की थी। कूटनीति फलदायी सिद्ध हुई। गृहमंत्री और राज्यपाल के तालमेल ने अवसर पाते ही बोम्मई सरकार का तख्ता पलट दिया।

कर्नाटक प्रकरण ने न केवल गृहमंत्री बूटा सिंह की दुरंदेशी दर्शायी, बल्कि उनकी कद-काठी का परिचय भी दिया और उसमें इजाफा भी किया। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बोम्मई सरकार गिरायी जाये या नहीं, इस मुद्दे पर पार्टी दो खेमों में विभाजित हो गयी थी। पार्टी के कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र पाटिल, आस्कर फर्नांडीस, शीला दीक्षित आदि तख्तापलट के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार ऐसा करने से हवा कांग्रेस विरोधी हो जायेगी। उनका दूसरा तर्क था कि २७ मार्च को जब विधानसभा का अधिवेशन होगा, तो सरकार खुद-ब-खुद गिर जायेगी। बूटा सिंह इस विचार से सहमत नहीं थे। मामले पर विचार करने के लिए कैबिनट की विशेष बैठक बुलायी गयी थी। इसमें शामिल एक मंत्री के अनुसार, "बूटा सिंह की दलीलों ने प्रधानमंत्री को तो अपने पक्ष में किया ही, अन्य उपस्थित लोगों को भी लाजवाब कर दिया।" बूटा सिंह की सीधी-सी रणनीति थी—जनतादल को चुनाव के समय साधनहीन बनाना और जनता में धारणा पैदा करना कि विपक्ष स्थायी सरकार नहीं दे सकता। कांग्रेस के लिए एक तीर से दो शिकार करने वाले गृहमंत्री की विपक्ष द्वारा भर्त्सना करना स्वाभाविक है।

गोरखालैंड आंदोलन और गृहमंत्री: उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के लाभ के लिए जो भूमिका उन्होंने दार्जिलिंग (प० बंगाल) व त्रिपुरा में निभायी, वह इससे भी अभूतपूर्व रही। प्रारंभ में

असुरक्षित गृहमंत्री : बूटा सिंह कमांडों से घिरे हुए

प० बंगाल की मार्क्सवादी सरकार के खिलाफ गोरखालैंड आंदोलन को भरपूर हवा दी। मकसद बहुत स्पष्ट था—मार्क्सवादी सरकार को सांसत में डालना और आगामी विधानसभा चुनाव में लाभ हासिल करना। किंतु पासा तब पलट गया, जब मार्क्सवादियों ने गोरखालैंड के मुद्दे को अपने पक्ष में कर कांग्रेस को चुनावी धूल चटा दी। इस अति संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र (दार्जिलिंग) में बढ़ती हिंसा ने केंद्र को अपने कदम वापस लेने पर विचार करने को बाध्य किया। कदम वापस ऐसे ढंग से लेने थे कि हल भी निकल आये और केंद्र की हेठी भी न हो। इसे सरअंजाम देने में गृहमंत्री ने महती भूमिका निभायी। सुलह-समझौतों से संबद्ध एक अधिकारी ने 'माया' को बताया कि बूटा सिंह ने एक ओर अपने मार्क्सवादी संबंधों-संपर्कों के जरिए प० बंगाल सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री ज्योति बसु को मनाया-पटाया, तो दूसरी ओर गुप्तचर एजेंसियों के सहयोग से न सिर्फ सुभाष घीसिंग पर नियंत्रण ही किया, बल्कि गोरखालैंड की मांग छोड़ने के लिए विवश भी। अंततः उनका भी विश्वास जीत ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करा लिये, जिसमें वास्तव में घीसिंग के पल्ले बहुत थोड़ा आया।

त्रिपुरा में तो और भी नायाब काम किया गया। वहां के टीएनवी उग्रवादियों को स्पष्टतया केंद्र का समर्थन प्राप्त था। यह विधानसभा चुनावों के शीघ्र बाद हुए उनके समझौतों से उजागर हो जाता है। उग्रवादियों की बढ़ती हिंसक वारदात ने दस वर्ष पुरानी मार्क्सवादी सरकार के मुख्यमंत्री, नृपेन चक्रवर्ती के हौसले पस्त कर दिये थे। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ उठाया गृहमंत्री बूटा सिंह ने। मरहम लगाने के बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री से अशांत क्षेत्र में सैन्य तैनाती की हस्तलिखित प्रति पर स्वीकृति (हस्ताक्षर) ले ली। यह नृपेन चक्रवर्ती सरकार के लिए मृत्युपत्र साबित हुआ।

तमिलनाडु की जानकी रामचंद्रन सरकार को गिराने में भी बूटा सिंह ने एक ओर तो अपने मंत्रालय की विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों और दूसरी ओर, वहां के राज्यपाल सुंदरलाल खुराना की सहायता ली। जानकार सूत्रों के अनुसार कर्नाटक की भांति उन्होंने तमिलनाडु में भी विधायकों पर जोर-जबर्दस्ती और खरीद-फरोख्त के इलजाम को जांच का मुद्दा बनाया। गृहमंत्री के इशारे पर गुप्तचर विभाग के लगभग आधा दर्जन अधिकारियों ने मद्रास के एक आलीशान होटल में पनाह ली। दो दिन के अंदर ही गृहमंत्री को समस्त जानकारियां मुहैया कर दी गयीं। इनको आधार बनाकर जानकी रामचंद्रन सरकार बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। गृहमंत्री की इस कार्रवाई से विपक्ष ही नहीं, उनकी अपनी ही पार्टी के लोग नाराज हो गये। शिवाजी गणेशन तो पार्टी से बाहर जा अलग पार्टी बना बैठे। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनावों में प० बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ी।

न सिर्फ विपक्ष, बल्कि अपनी ही पार्टी (कांग्रेस) द्वारा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने, हटाने, बचाने में भी बूटा सिंह की विवादास्पद भूमिका रही है। स्वयं उनके अनुसार गत तीन-चार वर्षों में महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण कांग्रेस-गढ़ में उन्होंने छह मुख्यमंत्रियों की अदला-बदली की है। गत वर्ष मप्र और बिहार में जिस प्रकार बिना किसी सुगबुगाहट के आधी रात में कांग्रेसी विधायकों को बिस्तर से उठाकर मोतीलाल वोरा की जगह अर्जुन सिंह की और बिंदेश्वरी दुबे की जगह भागवत झा की ताजपोशी की गयी, वह भी बूटा सिंह का ही कमाल था। किंतु इसी के चलते पार्टी में उनके विरोधियों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हुआ। मात्र एक वर्ष के अन्तराल में उपर्युक्त दोनों ही राज्यों में फिर नेतृत्व-परिवर्तन कराने गये गृहमंत्री

कठघरे में परिवार या गृहमंत्री

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन (रीको) की भिवाड़ी स्थित संयुक्त क्षेत्र की रुग्ण इकाई आर्यावर्त प्लाइवुड का जो सौदा, पिछले वर्ष केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के पुत्रों अरविंद सिंह और सरबजोत सिंह की जोरावर कम्पनी के साथ हुआ, उसकी कथा अखबारों में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ही क्यों प्रकाशित हुई ? इसके प्रकाशित होने के पीछे अन्य कारणों के अलावा मुख्यमंत्री पद को स्थायी मानकर मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का बूटा सिंह के खौफ से आजाद होने का हौसला भी हो सकता है।

राजस्थान विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति की जांच के दौरान यह मामला सामने आया, लेकिन उपक्रम समिति इस संबंध में कोई रिपोर्ट बनाती, इससे पहले जनता दल के समाजवादी घटक के नेता एवं विधायक प्रो० केदार, माणक चंद सुराणा और मोहन छंगाणी ने २० अप्रैल को एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के दबाव में आकर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 'रीको' के कब्जे की करोड़ों रुपए की सम्पत्तिवाली एक बंद इकाई, उनके लड़कों के स्वामित्ववाली कंपनी को नब्बे लाख की मामूली रकम में बेच दी।

बयान के अनुसार, अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 'रीको' के स्वामित्ववाली मेसर्स आर्यावृत प्लाइवुड लिमिटेड को बूटा सिंह के पुत्रों के स्वामित्ववाली कंपनी को कौड़ियों में बेच दिया गया। इन नेताओं के अनुसार आर्यावर्त प्लाइवुड लिमिटेड के पास कीमती विदेशी व स्वदेशी मशीनों के अलावा ६६ हजार वर्गमीटर जमीन भी है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह सौदा तय हुआ है, जबकि भारत सरकार के कंपनी कानून के तहत दिल्ली उच्चन्यायालय का आदेश है कि उक्त औद्योगिक इकाई का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इस आदेश के अनुसार मैसर्स आर्यावर्त प्लाइवुड लिमिटेड को तब तक नहीं बेचा जा सकता, जब तक वह अपनी तमाम देनदारियों से मुक्त न हो जाये। बयान में बताया गया कि उक्त कंपनी पर विभिन्न संस्थाओं की मूल धनराशि एक करोड़ बीस लाख रुपए और पचास लाख रुपए से ज्यादा ब्याज बकाया है।

बयान में कहा गया है कि दिल्ली के एक लकड़ी के व्यापारी धर्मवीर ने उक्त कंपनी से अपनी छह लाख, चालीस हजार रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए दिल्ली उच्चन्यायालय में मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे को सुनने के बाद उच्चन्यायालय ने सरकारी 'लिक्विडेटर' को आदेश दिया कि कंपनी की सारी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले ले तथा उसके विक्रय से जो राशि प्राप्त हो, उससे कंपनी की सभी देनदारियों को चुकता किया जाये।

बूटा सिंह के पुत्र अरविंद सिंह

आरोप: आरोप है कि 'रीको' ने दिल्ली उच्चन्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त औद्योगिक इकाई को गुपचुप बेच दिया। सौदे की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बयान में कहा गया था कि साधारणत: 'रीको' खस्ताहाल औद्योगिक इकाइयों का विक्रय जिन शर्तों पर करता है, उससे अलग हटकर विशेष प्रावधानों द्वारा मैसर्स आर्यावर्त प्लाइवुड लिमिटेड का मैसर्स जोरिन इम्पैक्स के लिए यशवर्धन (वायुदूत के प्रबन्ध निदेशक हर्षवर्धन के भाई) के नाम ९ दिसम्बर, १९८८ को विक्रय पत्र जारी किया गया। इस पत्र में कहा गया कि 'रीको' आर्यावर्त प्लाइवुड को ९० लाख में बेचने को तैयार है। क्रेता कंपनी इसकी चौथाई रकम २२ लाख ५० हजार रुपए नकद भुगतान करेगी और शेष ७५ प्रतिशत राशि ६ वर्षों में साढ़े बारह प्रतिशत की ब्याज दर के साथ तिमाही किश्तों में चुकायेगी। बयान के अनुसार, ''रीको' ने इस औद्योगिक इकाई को बेचने के लिए ९ सितम्बर, १९८८ को (इकानामिक टाइम्स में) विज्ञापन भी दिया था। इस विज्ञापन के फलस्वरूप २२ व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि 'रीको' के जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय पहुंचे।'' बताया जाता है कि सारा सौदा ९० मिनट में तय हो गया।

जनतादल के इन नेताओं का आरोप है कि 'रीको' की विक्रय शर्तों के अनुसार मैसर्स जोरिन इम्पैक्स सनमाइका वुड का उत्पादन करेगी। इसके विपरीत बूटा सिंह के पुत्रों ने वनस्पति घी बनाने के लिए केंद्र सरकार का आशय-पत्र प्राप्त कर लिया, जिसका कारखाना प्लाइवुड बनाने की कंपनी के स्थान पर लगाया जायेगा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर, १९८८ में सनमाइका वुड का उत्पादन करने के लिए जोरिन कंपनी यशवर्धन और बूटा सिंह के परिवार के सदस्यों ने ही मिलकर स्थापित की थी। लेकिन इसके पूर्व नवंबर, १९८८ में दोनों परिवारों ने मिलकर जोरावर वनस्पति लिमिटेड की स्थापना कर दी थी। आर्यावर्त प्लाइवुड का सौदा जोरिन कंपनी के नाम से किया गया था, जिसे बाद में जोरावर वनस्पति लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया।

बहरहाल, कथित राजनीतिक प्रभाव से हुए इस सौदे में कागजों में कोई अपराधी नजर आता है, तो वे हैं, 'रीको' के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। भिवाड़ी में लगनेवाले इस वनस्पति उद्योग की कथा में कई पेच हैं। मसलन, सनमाइका वुड उत्पादन करनेवाली फैक्ट्री वनस्पति उद्योग में कैसे बदल गयी ? वनस्पति उद्योग के निजी क्षेत्र में लगाने पर १९७६ से पाबंदी है, फिर बूटा सिंह के पुत्रों को यह लाइसेंस किस आधार पर मिला ?

२ अगस्त, १९८८ को 'रीको' ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया और २७ सितम्बर, १९८८ को उसे लाइसेंस दे दिया गया। गौरतलब बात यह है कि ऐसे उद्योग के लिए 'रीको' ने सन् १९८१-८२ में भी आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अब बूटा सिंह के पुत्रों को इस उद्योग के लिए भूमि चाहिए थी। इसके लिए 'रीको' ने ९ सितम्बर, १९८८ को अपनी दस बीमार इकाइयों की नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित करवाया। इस विज्ञापन के अनुसार २१ दिन के अंदर-अंदर पचास हजार की धरोहर राशि के साथ इच्छुक प्रस्तावकों के प्रस्ताव 'रीको' को प्राप्त होने चाहिए थे। इन रुग्ण इकाइयों में आर्यावर्त प्लाइवुड भी शामिल थी।

नीलामी की प्रक्रिया: 'रीको' में ऐसी नीलामी की प्रक्रिया यह है कि धरोहर राशि के साथ उपस्थित होनेवाले प्रस्तावकों के प्रस्तावों पर 'रीको' के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एक ही दिन, एक ही समय बातचीत करते हैं। रुग्ण इकाइयों की बोली लगायी जाती है और अपेक्षित भाव नहीं मिलते, तो नये टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं। आमंत्रित टेंडरों के आवेदकों से स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित उद्योग का अमुक राशि का प्रस्ताव आ चुका है। यानी नये प्रस्ताव उक्त राशि से अधिक के प्रस्ताव, धरोहर राशि के साथ आने चाहिए। 'रीको' ने आर्यावर्त के मामले में इस नीति का पालन नहीं किया।

'रीको' के दफ्तर में यह भी दर्ज है कि सन् १९८६ में यू०वी०इंटरनेशनल फर्म के वीके झुंझुनूवाला एवं विनोद झुंझनूवाला ने आर्यावर्त को बेहतर कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव रखा था। ऐसे में 'रीको' अध्यक्ष की यह सफाई वाजिब नहीं लगती कि आर्यावर्त का इससे ज्यादा मूल्य नहीं मिल सकता था।

केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के पुत्रों ने पांच-छः करोड़ की लागत से बननेवाले अपने वनस्पति उद्योग के लिए दिल्ली की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है। आरोप है कि वित्तीय संस्थाओं ने ऋण देने में जो

फुर्ती दिखायी है, वह तो गौरतलब है ही, पर साथ ही बूटा पुत्रों की एक नयी होशियारी सामने आती है। इस ऋण के लिए जोरावर वनस्पति ने अपने आवेदन में दर्ज किया है कि आशय पत्र की शर्त के अनुसार 'रीको' की भागीदारी २६ प्रतिशत होगी। 'रीको' को जब इस ऋण आवेदन की प्रति मिली, तो उसने २६ प्रतिशत पूंजी लगाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और भागीदारी दस प्रतिशत तक सीमित रखी। साथ ही दस प्रतिशत के शेयर भी उत्पादन शुरू होने के पांच वर्ष में बेच देने का अधिकार दर्ज किया।

यानी, बड़ी सफाई से निजी क्षेत्र के वर्जित उद्योग को संयुक्त क्षेत्र में लगाकर उसे निजी क्षेत्र में सौंपने का रास्ता 'रीको' के अधिकारियों ने राजनीतिक प्रभाव से मान लिया। वैसे, 'रीको' को मिले आशय पत्र के अनुबंध दो के अनुसार 'रीको' की भागीदारी २६ प्रतिशत होनी अनिवार्य है। इस संबंध में किसी भी फेरबदल से केंद्र सरकार को अवगत कराना आवश्यक है। पर बूटा सिंह के पुत्रों को लाभ देने के लिए रीको ने अपनी भागीदारी दस और जोरावर वनस्पति की ४१ प्रतिशत कर केंद्र को सूचित नहीं किया है। इस स्थिति में कानूनन आशय-पत्र रद्द हो जाना चाहिए जो नहीं हुआ है।

आर्यावर्त की संपदा : आर्यावर्त प्लाइवुड भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट नं० एसपीआई १४४ में स्थित है। ६६,४०० वर्गमीटर इसकी भूमि 'रीको' के आरक्षित मूल्य के अनुसार अस्सी रुपए प्रति वर्गमीटर है। वैसे नीलामी में यहां भूमि का भाव २५० रुपए प्रतिवर्ग मीटर है। इस तरह आरक्षित मूल्य में आर्यावर्त की भूमि ५३ लाख, १२ हजार रुपए की है, जबकि उसका बाजार मूल्य एक करोड़ ६६ लाख है। फैक्ट्री में २७७१.८० वर्ग मीटर का पक्का शेड है, वहीं ६८२.५० वर्ग मीटर में कार्यालय भवन तथा ११७६.९ मीटर लम्बी १.५ से १.९ मीटर ऊंची-पक्की चारदीवारी है। इन सबकी लागत तीस लाख के लगभग बतायी जाती है। इसके अतिरिक्त प्लाइवुड कारखाने की मशीनों की कीमत पचास-साठ लाख रुपए बतायी जाती है।

'रीको' दफ्तर से यह भी ज्ञात हुआ है कि २७ अप्रैल, १९८८ तक की स्थिति के अनुसार इस कारखाने में 'रीको', भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व आईसीआई के कुल २८.९५ लाख रुपए, भारत सरकार के ११.२८ लाख रुपए का अनुदान व 'रीको' तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के ऋण व ब्याज की कुल १३६.५२ लाख की राशि बकाया थी। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की १६५.४७ लाख की इस राशि के अलावा विद्युत मंडल के लगभग साढ़े नौ लाख, वन विभाग के ३.६२ लाख, बिक्री कर के दो लाख व उत्पादन कर के ५.७३ लाख बकाया थे। इस तरह फैक्ट्री की कुल देनदारियां १८६ लाख रुपएं हैं, जबकि 'रीको' को मिले हैं, कुल ९० लाख।

—ओम सैनी

को नाकों चने चबाने पड़े।

विफलता : अर्जुन सिंह को गत वर्ष मुख्यमंत्री बनाने में बूटा सिंह ने अहम भूमिका निभायी थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जब अर्जुन सिंह केंद्र में भारी पड़ने लगे और यह जरूरी समझा गया कि उन्हें भोपाल वापस भेज दिया जाये, तो पी शिवशंकर आदि सहमत न थे। उनका तर्क था कि एक बार वहां जमकर बैठ जाने पर अर्जुन सिंह को आवश्यकता पड़ने पर भी हटाना मुश्किल हो जायेगा। इस पर बूटा सिंह की सलाह थी कि अर्जुन सिंह को भोपाल भेजने में कोई 'रिस्क' नहीं। कारण, वक्त पड़ने पर उनके विभिन्न घोटालों को अदालत में ले जाकर उन्हें कभी भी काबू में किया जा सकेगा। अंततः हुआ भी यही। ताजपोशी के बाद जब अर्जुन सिंह ने मप्र में न केवल अपने पांव मजबूती से जमा लिये, बल्कि गुप्तचर सूत्रों के अनुसार विश्वनाथ प्रताप सिंह से एक कथित गुपचुप भेंट भी की, तो उन्हें विदा करना आवश्यक माना गया।

इस बार मुख्यमंत्री बदलना बूटा सिंह के लिये टेढ़ी खीर साबित हुआ। अर्जुन सिंह—समर्थक विधायकों ने न केवल उनकी बात मानने से इनकार किया, बल्कि उनके खिलाफ नारे भी लगाये, उन्हें अपशब्द कहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री बदलने के उनके अधिकार पर ही प्रश्नचिह्न लगाया। नियंत्रण से बाहर जाती स्थिति पर काबू पाने के लिए बूटा सिंह को गुप्तचर विभाग द्वारा तैयार की गयी उस गोपनीय फाइल का सहारा लेना पड़ा, जिसमें अर्जुन सिंह का कथित कच्चा चिट्ठा था। अपमान का कड़वा घूंट पी अर्जुन सिंह ने गद्दी तो खाली कर दी, पर उन्होंने पुराने प्रतिद्वंद्वी बूटा सिंह को जवाबी हमले का मुख्य निशाना बना लिया है।

इससे बड़ी असफलता का मुख गृहमंत्री को बिहार में तब देखना पड़ा, जब उनके तरकश के सभी तीर एक-के बाद-एक नाकाम साबित हुए और स्थिति बद से बदतर हो गयी। बिहार कांग्रेस के एक असंतुष्ट नेता ने 'माया' को बताया कि भागवत झा आजाद को गृहमंत्री हर हाल बचाने के लिए कटिबद्ध थे। इसके चलते न तो उन्होंने प्रधानमंत्री को स्थिति की सही जानकारी दी और न असंतुष्ट विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री से मिलने दिया। पटना पहुंचे, तो अपने अड़ियल रुख से न सिर्फ विधायकों को दबाने की कोशिश की, बल्कि अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी किया। नतीजतन, विद्रोही तेवर और तीखे व व्यापक हो गये। वे राजभवन में चार दिन पड़े रहे, पर कोई भी असंतुष्ट विधायक न तो उनसे मिलने गया, न ही किसी ने उनके अधिकार को स्वीकारा। जब उन्होंने विधायकों को विधानसभा भंग करने की धमकी दी, तो मामला एकदम हाथ से निकल गया। विधानसभा सत्र में 'वोट आफ अकाउंट्स' पारित करना तो दूर, उसमें भाग लेने को भी कोई तैयार न हुआ। हार कर एक ओर, विधानसभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी, तो दूसरी ओर, आलाकमान से बूटा सिंह को बिहार के मामले से अलग रखने की मांग की गयी।

हुकुम बजाने के लिए हरदम तैयार : राजीव गांधी और बूटा सिंह

राजस्थान में गृहमंत्री की विशेष कृपादृष्टि और दखलअंदाजी की चर्चा भी जोरशोर पर है। इस राज्य से न केवल कांग्रेस के वरन बूटा सिंह के अपने राजनीतिक, व्यावसायिक और पारिवारिक हित सीधे-सीधे जुड़े हैं। राज्य का जालौर जिला उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र (सुरक्षित) है। पारिवारिक व्यवसाय भी यहीं तेजी से फल-फूल रहा है (देखें बाक्स)। जानकार सूत्रों का दावा है कि पंजाब से दरबदर हुआ बूटा सिंह परिवार अंततः राजस्थान में पनाह लेना चाहता है।

वहां कांग्रेस की वर्तमान गुटबंदी के लिए बूटा सिंह को दोषी ठहराया जा रहा है। जिस अपमानजनक ढंग से हरिदेव जोशी को पदच्युत किया गया और हीरालाल देवपुरा को मिले अधिक वोटों के बावजूद शिवचरण माथुर को पहले गद्दीनशीं और अब असंतुष्ट पार्टी विधायकों के घोर विरोध के बावजूद उनको टिकाया जा रहा है, उससे गुटबंदी भी तेज हुई है और केंद्रीय गृहमंत्री का विरोध भी। राजस्थान के एक असंतुष्ट नेता के अनुसार, माथुर को टिकाये रखने के पीछे आलाकमान की इच्छा कितनी है, यह तो कहा नहीं जा सकता, किंतु केंद्रीय गृहमंत्री की इच्छा और नीति स्पष्ट है। उन पर आरोप है कि माथुर के सहारे उन्हें अपने राजनीतिक और व्यावसायिक हितों को सुदृढ करने में अधिक सुविधा है।

पंजाब में भूमिका : गृहराज्य (पंजाब) में भी गृहमंत्री की भूमिका ने उन्हें कम विवादास्पद नहीं बनाया है। विडंबना ही है कि १९६६ तक अकाली दल के सदस्य के रूप में रहने, पंजाबी सूबे की मांग

का जोरदार समर्थन करने और इस मांग को पूरा करानेवाले बूटा सिंह को आज पंजाब समस्या के समाधान में रोड़ा माना जा रहा है। आरोप स्वयं बूटा सिंह और उनके निकट सूत्रों के इस दावे से और विडंबनापूर्ण बन जाते हैं कि पंजाब समस्या में उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही है। कारण, पंजाब मसले का शुरू से सीधा संबंध प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय और पंजाब प्रशासन (मुख्यमंत्री अथवा राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल) से रहा है। नीति-निर्धारण और क्रियान्वयन दोनों में ही केंद्रीय गृहमंत्री और गृहमंत्रालय हाशिये पर रहे हैं।

कभी-कभार छिटपुट उपयोग के अलावा गृहमंत्री बूटा सिंह की पंजाब समस्या के समाधान में सीधी शिरकत हाल में बनी कैबिनट सलाहकार समिति (पंजाब मसले) का सदस्य बनने के बाद हुई है। किंतु इस समिति के भी अध्यक्ष वे नहीं, विदेश मंत्री नरसिम्हाराव हैं। अतः प्रश्न उठता है कि फिर बूटा सिंह को खलनायक क्यों करार दिया जाता है ?

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बूटा सिंह भले ही सीधे-सीधे पंजाब में सक्रिय न हों, किंतु परदे के पीछे से उनकी गतिविधियां निरंतर जारी रही हैं। यही कारण है कि पहले वे पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल अर्जुन सिंह और अब मौजूदा राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय की आंख की किरकिरी बने हैं। औपचारिक रूप से भी उनका उपयोग जब-जब किया गया, तो वे विवाद का मुद्दा बने। आपरेशन ब्ल्यू स्टार के तुरंत पश्चात अकालतख्त की मरम्मत जैसा नाजुक काम उनके ही सुपुर्द किया गया था। संता सिंह के माध्यम से शुरू की गयी इसी कार सेवा के लिए उन्हें (बूटा सिंह) तनखैया घोषित किया गया था। आज भी वे कौम से बहिष्कृत हैं। यही नहीं अकालतख्त की मरम्मत के लिए नियुक्त निर्माण कंपनी और उसके खर्चे के मुद्दे को उछाल कर अरुण नेहरू उन पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं।

अकाली दल सांसद रामूवालिया के अनुसार, 'बूटा सिंह वैसे आलोचना के पात्र नहीं, क्योंकि वे मात्र प्रधानमंत्री की नीतियों का पालन करते रहे हैं। किंतु जिस ढंग से उन्होंने सिखों के धार्मिक मामलों में सरकारी दखलअंदाजी की, उसने कुछ गलत धारणाओं-परंपराओं को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए सरबत खालसा पिछले १०० वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ था। बूटा सिंह ने अगस्त, १९८४ में सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके कुछ सत्तापरस्त धार्मिक लोगों को सामने ला कर सरबत खालसा करवाया। इसमें केंद्रीय मंत्री होते हुए भी सिर्फ प्रतिनिधि के रूप में वे खुद भी शामिल हुए। उसके बाद तो जैसे सरबत खालसा की बाढ़-सी आ गयी। इसी प्रकार बूटा सिंह की अकालतख्त की मरम्मत में भूमिका भी गलत थी और गलत बात के गलत नतीजे ही निकलते हैं।"

गलत नतीजों में सबसे प्रमुख यह है कि इससे गृहमंत्री के आतंकवादियों से संबंध-संपर्क तक जोड़े गये। जब उसकी चर्चा स्वयं बूटा सिंह से चली, तो उन्होंने इसे सरासर अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि वे और उनका परिवार तो आतंकवाद का भुक्तभोगी है, साथी कैसे हो सकता है (देखें साक्षात्कार) ?

अहमियत: प्रश्न उठता हैं कि जनाधार-विहीन और आरोपों-प्रत्यारोपों व विवादों के घटाटोप के बावजूद बूटा सिंह की इतनी चलती क्यों है ? विडबना ही है कि बूटा सिंह की शक्ति और विवाद का मूल स्रोत एक ही है—प्रधानमंत्री राजीव गांधी से निकटता। आज वे न केवल प्रधानमंत्री के प्रमुख संदेशवाहक हैं, बल्कि उनके एक इशारे पर हर प्रिय-अप्रिय, सहज-कठिन काम को सरंजाम देनेवाले भी। चहुं ओर से घिरे प्रधानमंत्री के रक्षाकवच भी हैं और प्रमुख राजनीतिक सलाहकार भी।

प्रधानमंत्री के एक निकट सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री राजीव गांधी शायद ही कोई कदम बिना गृहमंत्री की सलाह-मशविरे के उठाते हों। स्थिति ऐसी है कि न केवल उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों को हाशिये पर डाल रखा है, बल्कि राजनीतिक मसलों की कैबिनेट समिति के सदस्यों को भी लगभग निरर्थक बना दिया है। गृहमंत्री बूटा सिंह की तूती कितने जोरशोर से बज रही है, यह इसी बात से स्पष्ट होता है कि विपक्ष शासित राज्यों से संबंधित सांसतपूर्ण रणनीति बनाने और लागू करने में उनकी तो प्रमुख भूमिका है ही, पार्टी (कांग्रेस) एवं प्रशासन संबंधी मामलों में भी उनका दखल और असर कुछ कम नहीं।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार हाल में पार्टी महासचिव के पद पर एआर मल्लू की नियुक्ति के पीछे बूटा सिंह की प्रमुख भूमिका रही है। बावजूद इसके कि ५ पार्टी सांसद भी इस तैनाती से सहमत या प्रसन्न नहीं। सूत्रों के अनुसार मल्लू जब अपने पुराने राजनीतिक गुरु पी शिवशंकर के पास तैनाती के तुरंत बाद आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो उनका दोटूक जवाब था, "जब तुम्हें बूटा सिंह की छत्रछाया प्राप्त है, तो मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत ?"

इसी प्रकार कहा जाता है कि पंजाब के सांसद आरएल भाटिया का पिछले मंत्रिमंडल हेरफेर में मंत्री बनाया जाना लगभग तय था, किंतु बूटा सिंह का विरोध अततः कारगर साबित हुआ। भाटिया हाथ मलते रह गये। ऐसे ही केके तिवारी की हाल की सूचना-प्रसारण मंत्रालय में तैनाती भी बूटा सिंह की चाणक्य नीति के तहत हुई बतायी जाती है। कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करने का समाचार जिस अप्रभावी ढंग से रेडियो-टेलीविजन पर प्रसारित हुआ, उससे प्रधानमंत्री सचिवालय बेहद क्रुद्ध था। पहली झाड़ पड़ी सूचना प्रसारण मंत्री एचकेएल भगत को, जिन्होंने अपना गुस्सा उतारा सूचना प्रसारण सचिव पर और उन्होंने आड़े हाथों लिया रेडियो-दूरदर्शन अधिकारियों को। समस्त उठापटक में गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को समझा लिया कि इस चुनाव वर्ष में संचार माध्यमों के कुशल, सफल प्रयोग के लिए किसी तेजतर्रार आदमी की बेहद जरूरत है। नतीजतन केके तिवारी की रातोरात तैनाती हो गयी।

कृपाकांक्षी: बूटा सिंह का आशीर्वाद चाहनेवालों की कमी नहीं

दिलचस्प तथ्य यह है कि इस तैनाती के बाद विभागों का जो बंटवारा हुआ, उसमें मंत्रालय के सभी विभाग दोनों राज्यमंत्रियों—तिवारी व कृष्ण कुमार को बांट दिये गये। भगत के हाथ में सिर्फ संसद में सुलह-सफाई पेश करने का काम रह गया। जाहिर है, बूटा सिंह की इस कूटनीति से आहत भगत खून का घूंट पीने को विवश अवश्य हैं, किंतु जवाबी हमले का एक भी मौका चूकनेवाले नहीं।

गृहमंत्री के असर-रसूख का एक और नमूना पेश किया जाता है। राजस्थान के मौजूदा संकट का हल ढूंढने गये वीर बहादुर सिंह ने वहां का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री माथुर को बदलने का इशारा किया। किंतु दिल्ली लौटते ही उन्होंने गृहमंत्री का जो तेवर देखा, तो तुरंत शीर्षासन कर मुख्यमंत्री माथुर को छोड़, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गहलोत को बदलने और पूर्व मुख्यमंत्री व असंतुष्ट विधायकों के नेता हरिदेव जोशी को राज्यपाल के रूप में राज्य से दरबदर करने की सिफारिश करने में देरी नहीं की।

पार्टी और प्रशासन पर इस प्रकार जबर्दस्त वर्चस्व स्थापित करनेवाले बूटा सिंह का दूसरों की आंख की किरकिरी बन जाना स्वाभाविक है। विशेषकर जब उनकी कुरसी पर आंख लगाने वालों—अर्जुन सिंह, भजनलाल, बलराम जाखड़ और वसंत साठे—की कमी नहीं है। अधिकांश गृहमंत्री को फंसाने और उनके खिलाफ कुप्रचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ताजा-तरीन मिसाल ठक्कर आयोग रिपोर्ट के भंडाफोड़ के बवंडर के बाद मिली। विश्वसनीय सूत्रों ने 'माया' को बताया कि गृहमंत्री के 'शुभचिंतक' सहयोगी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक यह खबर पहुंचाने में कोताही नहीं बरती कि भंडाफोड़ में बूटा सिंह का हाथ है। यह दीगर बात है कि प्रधानमंत्री ने इस पर कान नहीं दिया।

उक्त सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ और संसदीय कार्यमंत्री एचकेएल

दाल नहीं गली : घीसिंग से समझौता वार्ता

भगत ने भंडाफोड़ के बाद एक ओर तो गृहमंत्री को समझाया कि उनकी तुरत-फुरत प्रतिक्रिया उचित नहीं होगी, दूसरी ओर, प्रधामंत्री के कान भरे कि बूटा सिंह उनकी रक्षा में आगे नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि वस्तुस्थिति समझने के बाद दोपहर बाद ही गृहमंत्री ने संसद में बोलना शुरू किया।

पंजाब से आये जाखड़ और बूटा सिंह का आपस में पुराना छत्तीस का रिश्ता बताया जाता है। दोनों के ही राजस्थान से सीधे-सीधे राजनीतिक और व्यावसायिक हित भी जुड़े हैं। इधर आरोप लगाया जा रहा है कि बूटा सिंह के बेटों से संबंधित 'रीको' विवाद के भंडाफोड़ के कागजात लोकसभा अध्यक्ष ने मुहैया किये थे। दूसरी ओर यह आरोप है कि जवाबी हमला गृहमंत्री ने चारा मशीन घोटाले के कागजात को सौंप कर किया, जिससे जाखड़ भी कठघरे में खड़े हो गये हैं। इससे भी बड़ा हमला बूटा सिंह पर अरुण नेहरू से चेक पिस्तौलों की सीबीआई द्वारा पूछताछ के दौरान तब हुआ, जब अरुण नेहरू ने विवाद का रुख उनकी ओर यह कहकर मोड़ दिया कि वे उन पर एक हथियार व्यापारी जाजोडिया के माध्यम से पिस्तौल खरीदने के लिए जोर डाल रहे थे। नेहरू वही व्यक्ति हैं, जिनके साथ बूटा सिंह ने गृहमंत्रालय के अतिरिक्त एशियाड में न सिर्फ मिलकर काम किया था, बल्कि उसकी सफलता का श्रेय भी हासिल किया था। कल के दोस्त आज के जानी दुश्मन बन गये हैं। अरुण नेहरू यदि अपने निष्कासन में बूटा सिंह को मूल कारण मानते हैं, तो बूटा सिंह के सामने प्रश्न आत्मसम्मान का है। इससे पूर्व अरुण शौरी अतिगोपनीय दस्तावेजों की सप्लाई में गृहमंत्री बूटा सिंह की भूमिका पर सीधा इशारा कर चुके थे। दोनों ही आरोपों ने बूटा सिंह की स्थिति को काफी नाजुक बनाया है।

प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त-मंत्री के रूप में उभरे बूटा सिंह की मौजूदा हैसियत के पीछे अनेक कारण गिनाये जाते हैं। सर्वप्रथम है, सर्वोच्च नेतृत्व के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, भक्ति और सेवाभाव जो श्रीमती गांधी के काल से आज तक अक्षुण्ण है। कदाचित प्रधानमंत्री और गृहमंत्री में विश्वास और तालमेल पारस्परिक उपयोगितावाद पर आधारित है। जनाधारविहीन बूटा सिंह के लिए एक मजबूत राजनीतिक खूंटे से बंधना जरूरी है। उनके जनाधारविहीन होने, गुटों और निहित स्वार्थों से रहित होने के कारण प्रधानमंत्री का विश्वास और वरदहस्त प्राप्त होना भी स्वाभाविक रहा।

कांग्रेस सांसद नरेश चन्द्र चतुर्वेदी के अनुसार, बूटा सिंह का प्रधानमंत्री के हृदय में घर बनाने में सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि 'उन्होंने सिख सांप्रदायिकता के आगे राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि समझा। यहां तक कि जब पांचों ग्रंथियों ने उन्हें और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को तनखैया घोषित किया, तो ज्ञानी जैल सिंह ने तो घुटने टेक दिये, किंतु बूटा सिंह ने सांप्रदायिक ताकतों के सामने सर नहीं झुकाया। इसके लिए वे अवश्य ही बधाई के पात्र हैं।'

बूटा सिंह की वर्तमान सुदृढ़ स्थिति का एक अन्य पहलू उस गृहमंत्रालय की सुपुर्दगी है, जिसके मातहत वे गुप्तचर एजेंसियां हैं, जिनका पार्टी और प्रशासन के मामले में उपयोग दिनोदिन बढ़ा है। एक कांग्रेसी नेता ने बताया, "सूचना ज्ञान है और ज्ञान ही शक्ति है।" गृहमंत्रालय की विभिन्न एजेंसियों-गुप्तचर विभागों द्वारा सूचना एकत्र कराने और उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में बूटा सिंह ने कभी कोताही नहीं की है। न ही मंत्रालय की पूरी ताकत जुटा शत्रु से निपटने में वे राई-रत्ती हिचकिचाये हैं।

जहां तक शत्रु से निपटने का प्रश्न है, गृहमंत्री ने पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री पर होनेवाले चौतरफा आक्रमण को न केवल अपनी ओर मोड़ा है, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। ऊर्जा राज्यमंत्री कल्पनाथ राय के अनुसार, "बूटा सिंह उन गिने-चुने मंत्रियों में एक हैं जो राजीव गांधी का खुलकर साथ दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिन्होंने वीपी सिंह और अरुण नेहरू जैसे जनघातियों के खिलाफ आज तक जबान नहीं खोली। इसके ठीक विपरीत बूटा सिंह हैं जो प्राण हथेली पर लेकर प्रधानमंत्री के रक्षाकवच बने हुए हैं और हरावल दस्ता भी।"

बूटा सिंह के पक्ष में दो अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं। एक तो वे सिख हैं और १९८४ के सिख विरोधी दंगों व उसके पूर्व की चंद अप्रिय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उनको गृहमंत्री बनाये रखने का एक मनोवैज्ञानिक लाभ है। दूसरे, वे हरिजन समुदाय से आये नेता हैं, जिससे कांग्रेस की कमजोर वर्ग-समर्थक छवि बनती है। कदाचित इसीलिए दर्जनों मंत्रिमंडल फेरबदल के बावजूद बूटा सिंह तीन वर्षों से अधिक समय से गृहमंत्रालय में जमे हुए हैं।

राजनीतिक महारत: बूटा सिंह की राजनीतिक सूझ-बूझ को भी पर्यवेक्षक उनकी अमूल्य थाती करार देते हैं। 'माया' से बातचीत के दौरान एक ने बताया कि इसका आधार भले ही गुप्तचर एजेंसियों द्वारा प्रेषित सूचनाएं रही हों, किंतु आज की राजनीति के तमाम पहलुओं, पेचीदगियों, हथकंडों को जानने समझनेवाले बूटा सिंह अपना निचोड़ पेश करते हैं जो अधिकांशतः मान लिया जाता है। कांग्रेस-एस सांसद उन्नीकृष्णन ने जोड़ा, "बूटा सिंह राजीव कैबिनेट में एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जो जोड़तोड़ में बेजोड़ हैं। इसी से वे सब पर, चाहे वे आतंकवादी हों, अकाली हों या अपने ही पार्टीजन, नियंत्रण कर लेते हैं। उनमें आत्मरक्षा की भावना भी अत्यधिक प्रबल है। इसका ताजा उदाहरण उन धवन से उनका सुलह-समझौता है, जिनके पीछे उनका मंत्रालय कुछ समय तक हाथ धोकर पड़ा था। अवसरानुसार रंग बदलना और प्रधानमंत्री की हां-में-हां मिलाते हुए दिन को रात कह देना उनकी अभिन्न शैली है।"

यह 'जीहुजूरी' ही उनको आलोचना और घृणा का पात्र बनाती है। विपक्षी नेताओं के अनुसार, बूटा सिंह ने गृहमंत्री और गृहमंत्रालय दोनों की प्रतिष्ठा का अवमूल्यन किया है। जनता दल सांसद जयपाल रेड्डी ने कहा कि गृहमंत्री के रूप में बूटा सिंह की तैनाती राजीव गांधी के राजनीतिक स्तर की परिचायक है। बूटा सिंह का न तो संसद में सम्मान है, न अपनी पार्टी में। राजीव गांधी के लिए उनकी उपयोगियता एक 'शाक आब्जर्वर', 'बुलडोजर' और हर जा-बेजा हुक्म बजानेवाले 'चाकर' से अधिक नहीं।"

यह वास्तविकता है कि पं० जवाहरलाल नेहरू के समय गृहमंत्री का ओहदा संभालनेवाले पटेल,, पंत और लालबहादुर शास्त्री जैसे ऊंची कद-काठीवाले अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे। श्रीमती गांधी के शासन काल में भी वाईबी चह्वाण और ब्रह्मानंद रेड्डी इस पद पर आसीन रहे। वाईबी चह्वाण कदाचित अंतिम सक्षम गृहमंत्री सिद्ध हुए। उसके बाद शनैः-शनैः गृहमंत्री और गृहमंत्रालय का तेजी से

सिफर से शिखर तक

गृहमंत्री की वर्तमान हैसियत के पीछे कुछ लोग चाटुकारिता और चालाकी की सम्मिलित भूमिका देखते हैं।

इतने बंदूकधारी घेर कर ले जा रहे हैं। लगता है आज कोई तगड़ा उग्रवादी पकड़ा गया है—जम्मू दंगों से आतंकित दुकानदार ने दरवाजे के पल्ले से बाहर झांकते हुए जब उक्त टिप्पणी की, तो उसने देश के अमन-चैन की जिम्मेदारी संभालने वाले गृहमंत्री बूटा सिंह को पहचानने में भारी चूक की थी। यह विडंबना ही है कि समूचे देश में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था की देखरेख करने वाले बूटा सिंह का अपना जीवन पूर्णतया असुरक्षित है। शक्ति और महत्व की दृष्टि से प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर माने जाने वाले गृहमंत्री का नाम आतंकवादियों की सूची में भी दूसरे नंबर पर ही है। निजी जीवन किस चिड़िया का नाम है, यह भी संगीनों के साये में जीवन बिताने वाले गृहमंत्री शायद भूलने लगे हैं। अभावग्रस्त हरिजन परिवार में जन्मे ५४ वर्षीय बूटा सिंह के लिए असुरक्षा की भावना कोई नयी नहीं। फर्क मात्र इतना है कि उस समय समस्या येन-केन-प्रकारेण जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाने की थी, जबकि आज उसे बचाये रखने की है। गांव-गांव कपड़ा बेच जीवन निर्वाह करने वाले पिता के इस पुत्र ने कभी भी गरीबी को मार्ग की बाधा नहीं माना। उनके अनुसार, "उसमें भी आनंद उठाया। किताब उधार ले उसे आद्योपांत पढ़ने और कंठस्थ करने का अपना ही आकर्षण था। अभाव को मैंने कभी महत्व नहीं दिया।" नतीजतन मैट्रिक की शिक्षा तक जूते न खरीद सकने वाले बूटा सिंह आज भी बड़ी-से-बड़ी मीटिंग में जूते उतारकर बैठने में झिझकते नहीं। गरीब-दुखियारों के प्रति सहानुभूति और सहयोग का बीजारोपण भी बचपन के अभावग्रस्त जीवन के दौरान ही हुआ।

पिता से भिन्न और बेहतर जीवन की आकाक्षा रखने वाले बूटा सिंह ने हर हाल पढ़ाई जारी रखी। न छह मील पैदल जाना भारी था, न किताब उधार लेकर पढ़ने में संकोच था। स्कूल के दिनों में ही कम्युनिस्टों की पत्रिका 'फुलवारी' में चपरासी का काम करने—फाइलें उठाने-धरने, मटकों में पानी भरने—को बूटा सिंह ने कभी छोटा नहीं समझा। यहीं ज्ञानी हीरा सिंह दर्द की छत्रछाया में उन्होंने पत्रकारिता का कखग सीखा। पढ़ाई और काम के बीच ही खालसा कालेज जालंधर से पंजाबी साहित्य में स्नातक की डिग्री और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। युवक बूटा सिंह की लगन और कर्मठता से प्रभावित प्रोफेसर गुरुबचन सिंह तालिब का जब बंबई तबादला हुआ, तो वे अपने विद्यार्थी को भी साथ लेते गये। उनकी छत्रछाया में राजनीतिशास्त्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बूटा सिंह के मन पर उनका प्रभाव और अमिट छाप अस्वाभाविक नहीं।

राजनीति में प्रवेश अकस्मात हुआ। जब पंजाबी सूबे की मांग तीव्र हुई, तो प्रताप सिंह कैरो ने पंजाब में उससे संबंधित सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। जवाब में सूबे के समर्थकों ने बम्बई से 'रंजीत' नामक साप्ताहिक शुरू किया, जिसमें बूटा सिंह की प्रमुख भूमिका रही। 'रंजीत' ने बूटा सिंह को न सिर्फ बलराज साहनी, राजिंदर सिंह बेदी, मुल्कराज आनन्द, हरमन सिंह नाज आदि से जोड़ा, बल्कि साहित्य और लेखन से भी जोड़ा। बूटा सिंह के काम और संगठन-क्षमता ने मास्टर तारा सिंह को इतना प्रभावित किया कि १९६२ के आम चुनाव में उन्होंने उन्हें अकाली पार्टी की ओर से मोगा सुरक्षित सीट का टिकट दे दिया। संसद में प्रवेश पाने वाले सांसदों में २६ वर्षीय बूटा सिंह सबसे कम उम्र के थे।

सांसद के रूप में पंजाबी सूबे के मुद्दे पर भेजे गये एक ज्ञापन ने बूटा सिंह की मुलाकात श्रीमती इंदिरा गांधी से करायी। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने में सफल रहे। इसके बाद ही अकालियों में पड़ी फूट के कारण पार्टी मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह के दो गुटों में विभाजित हो गयी। उठापटक से ऊबे बूटा सिंह को ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर द्वारा कांग्रेस में आने के लिए रजामंद करना कठिन न रहा। विशेषकर इसलिए कि प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री से भेंट और स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी। नतीजतन तत्कालीन संसदीय पार्टी सचिव कृष्ण चंद्र पंत (वर्तमान रक्षामंत्री) ने बूटा सिंह को कांग्रेस में भर्ती कर लिया। १९६७ का चुनाव बूटा सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। १९६९ में जब पार्टी का विभाजन हुआ, तो वे श्रीमती गांधी के साथ चले गये। तब से आज तक गाधी परिवार के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा बहुचर्चित भी रही है और विवादास्पद भी।

कांग्रेस में शीघ्र ही अपना स्थान बनाने में जो बूटा कामयाब हुए, तो फिर उन्हें आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा है। बूटा सिंह १९७४ में पहली बार रेल मंत्रालय में उपमंत्री नियुक्त हुए। १९७७ के चुनाव के कुछ समय पूर्व वे वाणिज्य मंत्रालय में चले गये। १९७७ के चुनाव की आंधी श्रीमती गांधी को ही नहीं, उनके सेवक को भी बहा ले गयी। पर इन दुर्दिनों में भी उन्होंने नेता का साथ न छोड़ा। इस तूफानी दौर में पार्टी के महासचिव के रूप में उन्होंने पार्टी की नैया अकेले ही खेयी। मेहनत का फल मीठा रहा। १९८० में रोपड़ का चुनाव जीत, वे फिर संसद में प्रवेश पा गये। कदाचित अपने सेवक के धैर्य के परीक्षार्थ ही श्रीमती गांधी ने उन्हें नयी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। यद्यपि अंतुले जैसों ने दो महीनों में ही रोना-पीटना आरंभ कर दिया था, किंतु बूटा सिंह के मुंह से उफ तक न निकली। साधना ८१ में सफल हुई। बूटा सिंह परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री हो गये।

परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, तत्कालीन परिवहन मंत्री एपी शर्मा ने सिंह को बड़ी कुशलता से हाशिये पर रखा। किंतु हाय-तौबा मचाने की जगह बूटा सिंह ने मुंह सील कर समय काटने में ही खैरियत समझी। धीरज रंग लाया और एशियाड ने भाग्य का एक नया दरवाजा खोल दिया। १९८१ में विद्याचरण शुक्ल की अध्यक्षता में बनी एशियाड समिति में बूटा सिंह उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। शीघ्र ही उन्हें न केवल समिति की अध्यक्षता ही मिली, बल्कि खेल मंत्री का पद भी। संजय गांधी के परमभक्त के उनके भ्राताश्री राजीव गांधी से संबंध एशियाड के दौरान ही बने, बढ़े।

उल्लेखनीय है कि एशियाड की तैयारी और सफलता को राजीव गांधी, अरुण नेहरू और अरुण सिंह की तिकड़ी ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार बूटा सिंह इस तिकड़ी के लिए एक बहुत ही प्रभावी हथियार

सिद्ध हुए। एशियाड सफल रहा और सफलता की लालिमा ने इस दौरान के स्याह-सफेद को ढांक दिया। पुरस्कारस्वरूप १९८३ में बूटा सिंह को निर्माण व आवास मंत्री के रूप में काबीना में प्रवेश मिल गया।

गांधी परिवार की सेवा का भरपूर अवसर उन्हें यहां भी मिला। आपरेशन ब्ल्यू स्टार के बाद अकालतख्त की मरम्मत का जिम्मा श्रीमती गांधी ने अपने इस विश्वस्त सेवक को ही सौंपा, जिसे उन्होंने बड़ी कुशलता से निभाया—बावजूद इसके कि उन्हें इस कारण अपने धर्म से ही बहिष्कृत कर दिया गया। नेता-सेवा की खातिर धार्मिक प्रवृत्ति वाले बूटा सिंह यह आघात भी सह गये। हिंदू-सिख दंगों में भी वे तटस्थ रहे।

राजीव गांधी ने प्रारंभ में उन्हें कृषि मंत्रालय ही सौंपा था। गृह मंत्रालय का जिम्मा उन्हें अप्रैल-मई १९८६ में मिला। उन दिनों बूटा सिंह पत्नी के इलाज के लिए लंदन गये हुए थे। टेलीफोन पर 'संत जी आप हमारे मंत्री बन गये' कहने वाले कोई अन्य नहीं, आज के जानी दुश्मन अरुण नेहरू ही थे। गृह मंत्रालय में अपने नेता राजीव गांधी के प्रति वफादारी दिखाने में बूटा सिंह ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। यदि आज बूटा सिंह उनके सबसे विश्वस्त मंत्री हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं। प्रधानमंत्री की नजरों में उनका महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि न केवल उनके पास गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, बल्कि देश की तीनों विषम और विस्फोटक-समस्याओं—पंजाब, रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद और जम्मू-कश्मीर—के समाधान में उनकी सीधी शिरकत है।

गृहमंत्री की वर्तमान हैसियत के पीछे कुछ लोग चाटुकारिता और चालाकी की सम्मिलित भूमिका देखते हैं। गृहमंत्री ने दो ही सिद्धान्त माने हैं—एक, कोई भी काम छोटा नहीं, दूसरे, नेता की हर आज्ञा उचित और शिरोधार्य है और इसी ने उन्हें जमीं से उठा आसमां पर बिठा दिया है।

यदाकदा क्रूर और कठोर निर्णय लेने वाले गृहमंत्री अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सुबह-शाम के पाठ के अतिरिक्त कुछ समय पूर्व तक मीटिंगों तक में गृहमंत्री को माला फेरते देखा जा सकता था। इस प्रवृत्ति का लाभ अनेक साधु-सन्त उठाते हैं— जिनके भरी सभा में पैर छूते बूटा सिंह हिचकिचाते नहीं। साधु-सन्तों के प्रभाव में वे अकसर शाकाहारी भी हो जाते हैं। धर्मपरायणता और गरीबी की याद के कारण ही बूटा के दरबार से कोई जल्दी खाली हाथ नहीं जाता। दो पुत्र और एक पुत्री के इस पिता के लिए परिवार की देखरेख भी इसी लगन से करना आश्चर्यजनक नहीं। सेवा परमो धर्मः के सिद्धांत को मानने वाले बूटा सिंह की लगभग हाथ जोड़े चिर परिचित मुद्रा 'संकट मोचन' हनुमान की ही याद दिलाती है।

—रंजना

अवमूल्यन हुआ और यह प्रधानमंत्री कार्यालय का एक पुछल्ला मात्र रह गया।

आज स्थिति यह है कि गृहमंत्रालय के तमाम निर्णय, यहां तक कि नियुक्तियां भी, गृहमंत्रालय से नहीं होतीं। लगभग सभी अहम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय में लिये जाने के बाद यहां भेजे जाते हैं और फिर यहां से प्रेषित होते हैं। यही नहीं, गृहमंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी गृहमंत्री नहीं, गुप्तचर विभाग का निदेशक हो गया है जो प्रधानमंत्री से सीधा संपर्क साधता है।

गृहमंत्री का एक प्रमुख राजनीतिक दायित्व शत्रु को मित्र बनाना है, किंतु बूटा सिंह को इसमें मात मिली है। साथ ही वे अपने मित्रों—विशेषकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट सहयोगियों को हाशिये पर डालकर अपना शत्रु बना बैठे हैं। नतीजतन हर मंत्रिमंडलीय फेरबदल के पूर्व गृहमंत्रालय से उनकी विदाई की चर्चा भी जोरों से चल पड़ती है। स्मरण रहे कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान बूटा सिंह का नाम प्रत्याशी के रूप में उनके सहयोगियों द्वारा जब जोरशोर से उछाला गया था, तो उनकी नीयत बूटा सिंह को उस ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित करने की अपेक्षा, उन्हें सक्रिय राजनीति से अलग-थलग करने की अधिक थी। कुछ समय पूर्व जब पार्टी में अन्तर्कलह और विद्रोह चरम पर पहुंच रहा था, उस समय भी बूटा सिंह को पार्टी का कामकाज संभालने की जिम्मेदारी दिये जाने की खबर गरमायी थी। औपचारिक कारण यही बताया जा रहा था कि सिर्फ उनमें ही पार्टी का संगठन चुस्त दुरुस्त कर उसे चुनाव के लिए तैयार करने की क्षमता है। किंतु इसके पीछे उनको शक्तिमान गृहमंत्रालय और सरकार से अलग करने का मंशा किसी से छिपा न था।

> **बूटा सिंह गृहमंत्री रहेंगे या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु जब तक वे गृहमंत्री रहेंगे, हमलों से नहीं बच सकते। अकाली सांसद रामूवालिया के अनुसार, "बूटा सिंह की भूमिका राजनीतिक फुटबाल के मैच में उस सेंटर फारवर्ड खिलाड़ी की है, जिसका काम प्रतिद्वंद्वी टीम के गोल पर लगातार धावा बोल गोल करना है। इसमें प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उनको घेरा जाना खेल नियम के अनुसार स्वाभाविक है।"**

एक बार फिर इन दिनों राजधानी के सत्तागलियारों में यह अफवाह गर्म है कि शीघ्र ही बूटा सिंह को गृहमंत्रालय से अलग कर दिया जायेगा। ऐसी चर्चा चलानेवाले इसका कारण उनके मुंहफटपन, घमंड और पार्टीजनों तथा प्रधानमंत्री के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिशें बताते हैं। एक जानकार सूत्र ने इसे अपरिहार्य बताते हुए 'माया' से कहा कि स्थिति ठीक अर्जुन सिंह जैसी है, जिन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष के अपने कार्यकाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के चक्कर में ऐसा एकाधिकारपूर्ण वातावरण बना लिया था, जिससे अधिकांश पार्टीजनों में असंतोष इतना गहराया कि अंततः पार्टी अध्यक्ष के पद से उन्हें हटना पड़ा। ठीक यही दशा आज बूटा सिंह की बतायी जाती है। उनके आलोचक कहते हैं कि कहने को तो वे प्रधानमंत्री की नीतियों को लागू करते हैं, पर इसकी आड़ में चलाते अपनी राजनीति ही हैं। कैबिनेट में सब उनके खिलाफ नंगी तलवार लिये खड़े हैं। प्रश्न यह है कि क्या बूटा सिंह का अर्जुन सिंह जैसा हश्र होगा?

जवाब में एनसी चतुर्वेदी बोले, "बूटा सिंह को मैंने वर्षों से सत्ता के भीतर-बाहर देखा-परखा है। मेरे ऊपर उनकी विनम्रता, सदाशयता और सहयोगात्मकता की छाप है। घमंड या दुर्भावना उनमें मुझे नहीं मिली। यह अवश्य है कि गृह मंत्रालय से जुड़े हर छोटे-बड़े मसले को वे जिस दृढ़ता से निपटाते हैं, उससे कुछ लोगों को पहुंची हानि के कारण उनका विरोध कुछ बढ़ा है। बूटा सिंह की समस्या यह है कि हमला राजनीति के अतिरिक्त व्यक्तित्व और व्यवसाय को भी लपेटने लगा है।" प्रश्न यह है कि इस दलदल से वे कब और किस प्रकार उबर पायेंगे और इनके चलते प्रधानमंत्री कब तक उन पर अपना वरदहस्त बनाये रखेंगे? फिलहाल सूचना यही है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री को आक्रमण का लक्ष्य न बनाने का आदेश वरिष्ठ पार्टी नेताओं को जारी कर दिया है। किंतु बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी!

बूटा सिंह गृहमंत्री रहेंगे या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु जब तक वे गृहमंत्री रहेंगे, हमलों से नहीं बच सकते। अकाली सांसद रामूवालिया के अनुसार, "बूटा सिंह की भूमिका राजनीतिक फुटबाल के मैच में उस सेंटर फारवर्ड खिलाड़ी की है, जिसका काम प्रतिद्वंद्वी टीम के गोल पर लगातार धावा बोल गोल करना है। इसमें प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उनको घेरा जाना खेल नियम के अनुसार स्वाभाविक है।"

—रंजना कक्कड़,
त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव के साथ

साक्षात्कार : बूटा सिंह

मैंने आठ-दस मुख्यमंत्री बदले हैं

माया: आप अब तक के सर्वाधिक विवादग्रस्त गृहमंत्री क्यों कहे जाते हैं? कारण पद, कार्यशैली या आपका व्यक्तित्व है?

बूटा सिंह: कदाचित तीनों की ही मिलीजुली भूमिका है, किंतु पद को मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं। गृहमंत्री की भूमिका ऐसी है, जिसमें उसे कुछ ऐसे काम करने, ऐसे फैसले लेने होते हैं, जिनमें वह सबको खुश नहीं कर सकता। संविधान के अंतर्गत उसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बनाये रखना पड़ता है। जितने भी विवादग्रस्त विषय होते हैं, चाहे वे राज्य व राज्य के बीच हों या केंद्र व राज्य के बीच उनमें उसे ही मध्यस्थ होना पड़ता है। केंद्र के दिशानिर्देशों को राज्यों द्वारा लागू कराना भी गृहमंत्री का ही काम है। इसके लिए या तो वह प्रेरणा, प्रोत्साहन का इस्तेमाल करता है या आदेश। मैं जो कुछ भी करता हूं, उसके पीछे पद का दायित्व और देश का हित होता है।

माया: अभी तो लगता है कि आपकी भूमिका मूलतः राज्यों को स्टीमरोलर (दमन) करते रहना है?

सिंह: स्टीमरोलर तो हिंदी में 'दलन मलन' होता है और वह मैं नहीं करता। मेरा लक्ष्य यह है कि देश की धारा एकजुट होकर बहे। मेरी अपनी भूमिका इसमें उस संचालक की है, जिसे गाड़ी खींचनी है। कभी सवारी खुशी से बैठती है और कभी उसे लेकर चलना पड़ता है। इसमें राष्ट्रहित को मैं सर्वोपरि और धर्म से भी ऊपर मानता हूं।

माया: किंतु विपक्ष का आरोप है कि आप केंद्र और कांग्रेस पार्टी के हित में काम करते हुए विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं।

सिंह: केंद्र के हित में काम करना मेरा कर्तव्य है। केंद्र राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाये रखने की एक धुरी है। यदि यह धुरी ही कमजोर होगी, तो प्रांत चल नहीं सकते। किंतु यह कहना कि मैं पार्टी के फायदे के लिए काम करता हूं, निराधार है। मैं पार्टी के निर्देशों को केवल मार्गदर्शक मानता हूं। नजर सदैव राष्ट्रीय हित पर रहती है।

माया: प० बंगाल की गोरखालैंड समस्या, त्रिपुरा में चुनाव पूर्व सैन्य बल की तैनाती, असम में बोडो आंदोलन, तमिलनाडु में जानकी सरकार और हाल में कर्नाटक सरकार की बर्खास्तगी में गृहमंत्रालय और उससे संबद्ध एजेंसियों की ही भूमिका बतायी जाती है।

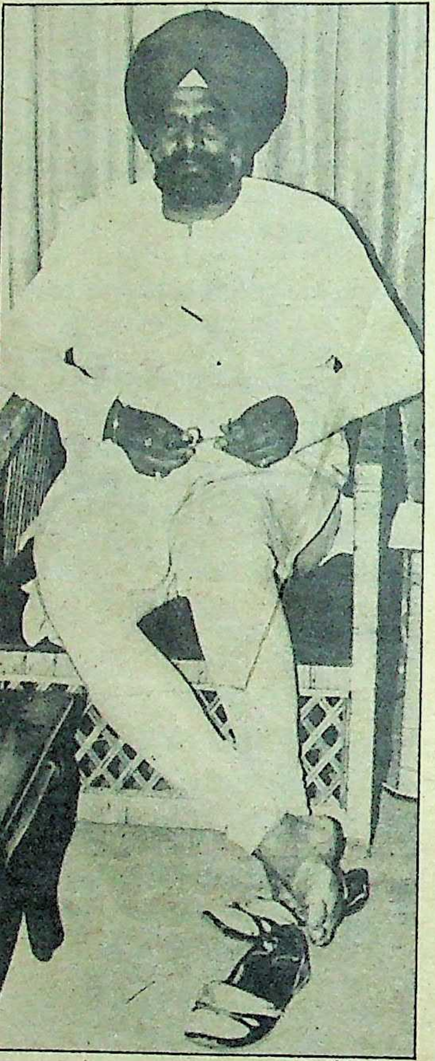

छाया : गिरीश श्रीवास्तव

सिंह: यह सही नहीं। गोरखालैंड की समस्या और मांग तो बहुत पुरानी है—सुभाष घीसिंग के उदय से भी पुरानी। दिलचस्प बात यह है कि स्वयं मार्क्सवादी पार्टी के एक सांसद ने संसद में इस संबंध में एक निजी प्रस्ताव पेशकर इसका ढांचा तक प्रस्तुत किया था। यही नहीं प० बंगाल विधानसभा में इस संबंध में एक सर्वदलीय प्रस्ताव भी पास हुआ था। विवाद तब शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया था कि गोरखा आंदोलन राष्ट्र-विरोधी नहीं है। ऐसा उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह के व्यापक दौरे और अध्ययन के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट के पश्चात कहा था। इसके अनुसार वहां के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए राजनीतिक कदम उठाने आवश्यक थे। जब प० बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए, तो मार्क्सवादी पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए कहा था कि राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी प० बंगाल का विभाजन कर गोरखालैंड बनाना चाहती है। इसलिए समस्त बंगालियों के वोट हमारे खिलाफ गये। फायदा मार्क्सवादियों ने उठाया, हमने नहीं।

माया: किंतु चुनावी लाभ न मिलने के बाद ही केंद्र के दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों आया?

सिंह: नहीं। यह बिलकुल गलत बात है। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि चुनावी लाभ के लिए हम इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहते। किंतु स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं का समुचित समाधान होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक था कि भारत सरकार और सीपीएम मिलकर हल निकालते। हम निरंतर प्रयास करते रहे। अन्ततः ज्योति बसु को समझौता वार्ता में शामिल होना पड़ा। चार-पांच महीने तीनों के बीच बात चली। सुभाष घीसिंग व उनके साथियों ने भी माना कि हिंसा व पृथकतावाद का रास्ता गलत है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से गोरखालैंड की मांग छोड़ी। इस प्रकार हम दोनों के बीच समझौता करा सके। समूचे प्रकरण में कांग्रेस का तो नुकसान ही हुआ, क्योंकि चुनाव में हमें बहुत कम वोट मिले थे।

माया: क्या इसी नुकसान का बदला लेने के लिए आपने त्रिपुरा में सेना भेजकर चुनाव कराया और वहां की मार्क्सवादी सरकार को हरा दिया।

सिंह: मैं इसे हार का बदला नहीं कहता। यह न सीपीएम की जीत है, न कांग्रेस की, बल्कि राष्ट्र की जीत है। त्रिपुरा में काफी समय से उग्रवादी गतिविधियां चल रही थीं, जिससे काफी लोग मारे जा रहे थे। हमने राज्य सरकार के साथ हालात पर नियंत्रण पाने की बड़ी कोशिश की। इसी बीच विधानसभा चुनाव आ गये और उग्रवादियों की गतिविधियों में भी सहसा तेजी आ गयी। इस पर हमारी कई बैठकें हुई। हमने पंजाब की मिसाल देते हुए बताया कि जब तक हम सैन्य टुकड़ियों को और हथियार नहीं देंगे, तब तक गंभीर हुई स्थिति में

सुधार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति दी थी।

माया: क्या इस सहमति को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री को बेवकूफ बनाया गया, बहलाया-फुसलाया गया अथवा उनके साथ धोखाधड़ी हुई? क्योंकि मार्क्सवादियों का आरोप है कि चुनाव-पूर्व फौज की तैनाती का व्यापक असर हुआ था!

सिंह: मैं घटिया कार्रवाई कभी नहीं करता। नृपेन चक्रवर्ती तो हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हम भला उनके साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकते हैं?

माया: तो क्या उन्होंने सैन्य बल की तैनाती पर दस्तखत नासमझी में किये?

सिंह: नासमझी का सवाल नहीं है। बैठक के एक दिन पूर्व ११ हत्याएं हुई थीं। अगले दिन ३०। मुख्यमंत्री ने खुद माना कि स्थिति गंभीर है और नियंत्रण के बाहर हो गयी है।

माया: फिर आज सारा दोष आपके मत्थे क्यों डाला जा रहा है?

सिंह: चूंकि, चुनाव हारे, इसलिए उन्हें (मार्क्सवादियों को) किसी-न-किसी को बलि का बकरा बनाना ही था। वैसे, स्वयं मार्क्सवादी सांसद समर मुखर्जी ने गृहमंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में इस बात से इनकार किया कि सेना ने त्रिपुरा विधानसभा के चुनावों में परिणामों को प्रभावित किया। हां यह जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोटाला किया। यह आरोप तो हर पार्टी चुनावों में दूसरी पार्टी पर लगाती ही है।

माया: असम सरकार तो अभी से ही बोडो आंदोलन के लिए केंद्र और गृहमंत्रालय की एजेंसियों को दोषी ठहरा रही है।

सिंह: असम गण परिषद वाले शायद भूल गये हैं कि यह आंदोलन स्वयं उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी प्लेन्स ट्राइबल्स कौंसिल (पीटीसी) के साथ शुरू किया था और उसकी मदद से उसने विधानसभा चुनाव भी जीत लिया था, किंतु कुछ नीतियों पर अमल के मसले पर दोनों में मतभेद हो गया। युवाओं-छात्रों के 'पीटीसी' से जुड़ने से यह खाई और बढ़ी। अंततः आल बोडो स्टूडेंटस यूनियन बन गयी। हमारे पास जब-जब ज्ञापन और मांगपत्र आये हैं, हमने मुख्यमंत्री को तुरंत आगाह किया है और स्थिति को नियंत्रण से निकलने न देने की सलाह दी है। हम से जब-जब मदद मांगी गयी है, हमने दी है। परसों की मुलाकात में मैंने मुख्यमंत्री से पुनः कहा है कि हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे।

माया: फिर असम सरकार केंद्र को दोषी क्यों ठहरा रही है?

सिंह: कारण सीधा है। असम सरकार न केवल बोडो आंदोलनकारियों, बल्कि जनता की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने में बुरी तरह विफल रही है। आज अल्पसंख्यक आदिवासी और वहां बसे गैर असमिया सभी सरकार के खिलाफ हैं। राज्य सरकार एक दिन भी ठीक से शासन नहीं कर पायी है। असम गण परिषद में स्वयं अंतर्विरोध और कलह है। आपसी सर-फुटौव्वल के चलते वहा जनसमस्याओं को हल करने की कोशिश ही नहीं हो रही। दुर्भाग्यवश इनके पास प्रशासनिक अनुभव की भी कमी है, वरना समस्या इतनी जटिल नहीं। जरूरत है, यह जनविश्वास हासिल करने की कि सरकार वास्तव में समाधान चाहती है।

छाया: प्रभाकर

> इस पार्टी का मृत्युपत्र तो उसी दिन जारी हो गया, जिस दिन जनतादल और जनता पार्टी दो अलग-अलग संगठन हो गये। किराये के टट्टुओं (विधायकों) से कितने दिनों तक वफादारी की उम्मीद की जा सकती है। विशेषकर तब, जब हेगड़े ने कभी बोम्मई को मुख्यमंत्री माना ही नहीं। दो नेताओं की लड़ाई का देवगौड़ा ने फायदा उठाया। कांग्रेस से इसका कुछ लेना-देना नहीं था।

माया: अविश्वास तो विपक्षी राज्य सरकारों का केंद्र में लगातार बढ़ा है, विशेषकर तमिलनाडु की जानकी रामचंद्रन सरकार और कर्नाटक की बोम्मई सरकार के तख्तापलट के बाद।

सिंह: जानकी सरकार को हमने बर्खास्त नहीं किया। वह खुद अपने कर्मों से गिरी है। जिस जानकी सरकार को हमने पूर्ण समर्थन दिया, उसको क्या जरूरत थी कि हमारे ही विधायकों का किडनैप (अपहरण) करती? बावजूद इसके कि स्वयं प्रधानमंत्री ने उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया था। टेलीफोन करके अपने ही पांच विधायकों को बर्खास्त कराने का काम उन्होंने खुद किया था, हमने नहीं। विधायकों के व्यापक निलंबन के बाद सदन में हुआ हंगामा अभूतपूर्व रहा। मेरा इसमें क्या दोष या हाथ रहा? कर्नाटक के मामले में स्वयं जनतादल के विभिन्न नेताओं के बयानों से ही यह स्पष्ट है कि बोम्मई सरकार अपने ही अंतर्विरोधों और आपसी कलह के कारण गिरी। रही मेरी भूमिका की बात, तो मैं शपथ सहित कह सकता हू कि मैं देवगौड़ा से आज तक कभी नहीं मिला।

माया: केंद्र पहले से ही गिद्ध दृष्टि लगाये बैठा था और इस मौके का आपने भरपूर लाभ उठाया।

सिंह: आप उस पार्टी की बात करती हैं, जिसको एफीडेविट (हलफनामा) देने के लिए अपने ही विधायकों को पैसे देने पड़े थे। इस पार्टी का मृत्युपत्र तो उसी दिन जारी हो गया, जिस दिन जनतादल और जनता पार्टी दो अलग-अलग संगठन हो गये। किराये के टट्टुओं (विधायकों) से कितने दिनों तक वफादारी की उम्मीद की जा सकती है। विशेषकर तब, जब हेगड़े ने कभी बोम्मई को मुख्यमंत्री माना ही नहीं। दो नेताओं की लड़ाई का देवगौड़ा ने फायदा उठाया। काग्रेस से इसका कुछ लेना-देना नही था।

माया: कहा जाता है कि बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी के प्रश्न पर स्वयं कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बंट गयी थी। पर अंततः आपकी चली और सरकार का तख्ता पलटने का निर्णय ले लिया गया।

सिंह: तख्ता पलटने जैसी कोई बात नहीं होती। सच यह है कि गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि कर्नाटक में संवैधानिक 'ब्रेकडाउन' (गतिरोध) हो गया है। अतः राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। कैबिनेट में इस पर विचार हुआ और सर्वसम्मति से फैसला हुआ।

माया: कांग्रेस-शासित राज्यों में मुख्यमंत्री हटाने, बनाने व बचाने का आरोप भी आपके सर क्यों जाता है?

सिंह: मैं पार्टी का एक अदना सा सेवादार हूं। ये फैसले आलाकमान करता है। पार्टी का जो भी आदेश होता है, मैं अपने व्यक्तित्व को अलग रखकर उसका पालन करता हूं! मैं यह नहीं देखता कि इससे मुझे क्या नफा-नुकसान होगा, बल्कि मैं देखता हूं कि इससे प्रदेश और पार्टी को क्या लाभ होगा? मैंने कभी कोई निजी लाभ नहीं उठाया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मेरा कहीं कोई गुट नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले तीन-चार सालों में मेरे हाथों छह मुख्यमंत्री बदले गये हैं। यह तो नहीं

कहा जा सकता कि मैं महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हूं। मैंने जो किया, वह आलाकमान और पार्टी के हित के लिए और वह भी पूरी तरह निडर होकर किया।

माया : क्या आलाकमान ये काम आपके सुपुर्द इसलिए करता है कि आप एक तगड़े 'मैनीपुलेटर' हैं और हर हथकंडा अपना कर अपना काम साध लेते हैं?

सिंह : मैं 'मैनीपुलेट' नहीं करता। कांग्रेसजनों को सीधे-सीधे बताता हूं कि क्या पार्टी के हित में है और क्या प्रदेश के। कांग्रेसजनों को मेरे प्रति प्यार मेरी बात मनवा देता है।

माया : प्यार या डर?

सिंह : मुझसे डर कैसा? न तो मैं टिकट बांटनेवालों में से हूं, न ही मैं राज्यों की कैबिनेट बनवाता हूं। हां, यह अवश्य है कि मैं बात को घुमाता-फिराता नहीं, दो-टूक तरीके से सब बातें कहता हूं और लोग मेरी बात मान जाते हैं।

मैं हमेशा प्रधानमंत्रीजी (राजीव गांधी) और श्रीमती गांधीजी का शुक्रगुजार रहूंगा कि मुझ पर कृपाकर सेवा का मौका दिया। शायद मैं इसके काबिल भी नहीं था। यह परिवार देश की एकता अखंडता का प्रतीक है। इसीलिए मेरी इनके प्रति पूर्ण निष्ठा है। इनके हर आदेश का पालन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

माया : क्या आपकी सफलता का राज प्रधानमंत्री से निकटता नहीं?

सिंह : उनका तो मुझे बहुत सहारा है। लेकिन मैं उनका नाम कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कम-से-कम आठ-दस मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन कोई कांग्रेसजन कह दे कि मैंने प्रधानमंत्री का नाम लेकर काम करवाया है।

माया : अकलमंद को इशारा काफी होता है। जो आप कहते और करते हैं, उसे लोग प्रधानमंत्री का इशारा समझते हैं।

सिंह : आदेश हमेशा नेता का ही होता है। मैं परिस्थिति के मुताबिक तर्क-वितर्क करता हूं। सौभाग्यवश बिहार को छोड़कर हर जगह मेरे तर्क खरे उतरे हैं।

माया : आपकी पार्टी में भी आपका विरोध बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है?

सिंह : मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है और यदि है, तो मैं ऐसी बातों की परवाह नहीं करता। मैं तो अपने दायित्वों को पूरा करने में विश्वास करता हूं।

माया : ऐसा आरोप है कि कांग्रेस-शासित राज्यों में भी आप हस्तक्षेप करते हैं?

सिंह : गृहमंत्री के रूप में सभी राज्यों के साथ मेरा संबंध रहता है। कांग्रेस-शासित राज्यों में कांग्रेस की ओर से ड्यूटी लगती है। कैबिनेट के हर सदस्य के जिम्मे एक-एक राज्य है। सब लोग पार्टी आलाकमान के आदेश का पालन करते हैं।

माया : किंतु, जितने बहुचर्चित और विवादग्रस्त आज आप हैं, उतना कोई अन्य क्यों नहीं?

सिंह : विवाद के दो पहलू हैं, खाली राजनीतिक पहलू नहीं। कुछ अखबारवाले भी मुझसे अधिक प्यार करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग का जब केस चल रहा था, उस समय मैं आवास मंत्री था और मुझे 'स्टैंड' (फैसला) लेना पड़ा। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। उस समय इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मैं उनको छूट दूं। किंतु मैंने कहा कि जो तथ्य है, वही मेरा स्टैंड है। न किसी का पक्ष लूंगा, न किसी का विरोध करूंगा। अंततः केस उनके खिलाफ गया। तब से गोयनका परिवार मेरे खिलाफ है। वे कोई-न-कोई रास्ता ढूंढ़ते रहे, पर कुछ कर नहीं पाये। और जब से गुरूमूर्ति का किस्सा उठा और मैंने संसद में हिम्मत से इस केस को पकड़ा और मार्च, १९८७ में जब इंडियन एक्सप्रेस पर छापा पड़ा, तब से ये लोग कुछ ज्यादा ही मेरे खिलाफ हो गये। फिर इसके बाद विश्वनाथ का किस्सा हुआ जिसका मैंने डटकर जवाब दिया कि विश्वनाथ और इनकी (गोयनका परिवार की) आपस में कोई सांठगांठ है। इसलिए यह गुट मेरे खिलाफ है।

माया : आपकी पार्टी में भी कुछ लोग आपके खिलाफ इसलिए बताये जाते हैं, क्योंकि कुछ को आपने हाशिये पर डाल दिया है और कुछ की नजर आपकी कुरसी पर है।

सिंह : यह बिलकुल गलत बात है। न तो मैं किसी को हाशिये पर डाल सकता हूं और न डालता हूं। यह मेरा तरीका नहीं है। यदि कोई अपने काम में पीछे हट गया हो, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हमेशा मेरी कोशिश यह रहती है कि जो मेरे सहयोगी हैं, उन्हें मैं अधिक-से-अधिक सहायता दूं और उनकी मदद करूं।

माया : हाल में आपके परिवार संबंधी व्यावसायिक घोटालों के प्रकाशन पर आपकी चुप्पी क्या आपकी स्वीकारोक्ति नहीं?

सिंह : मैं यह ठीक नहीं समझता कि जो कुछ छपे, उसका मैं स्पष्टीकरण देता फिरूं। यदि कुछ गलत किया गया है, तो उसके लिए कानून भी है और सजा भी मिलनी चाहिए। भले ही वह गृहमंत्री के बच्चे क्यों न हों? जो कुछ छपा है, वह तथ्य है और वह राज्य सरकार के पास है और केंद्र के भी। इस पर मेरा टिप्पणी करना निरर्थक है।

माया : तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपके बच्चों के साथ पक्षपात हुआ और नियम कानून भंग किये गये?

सिंह : यह कहां लिखा है कि उनके साथ पक्षपात हुआ है? न कहीं नियम भंग करने और नीतियां बदलने की बात ही छापी गयी। केवल सबसे बड़ा तथ्य यह सामने आया है कि वे मेरे बच्चे हैं और उनका दोष यह है कि सार्वजनिक नीलामी में जहा २०-२२ पार्टियां शामिल थीं, आम आदमी की तरह बोली लगाकर उन्होंने एक बंद पड़ी मिल को खरीदा है।

माया : किंतु आरोप है कि सौदा उचित मूल्य से बहुत कम दाम में हुआ।

सिंह : सार्वजनिक नीलामी में कम और ज्यादा पैसे का सवाल कैसे उठता है? सर्वाधिक बोली लगानेवाले के साथ सौदा हो जाता है।

माया : बात मात्र इस सौदे की ही नहीं, उसकी जमीन पर एक दूसरी नयी मिल लगाने की भी है।

सिंह : इस सौदे की यह शर्त भी थी कि जो पार्टी यह मिल लेगी, उसे दूसरी मिल भी लगानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों खाद्य तेल के लाइसेंस देने की नीति बन गयी। यह लाइसेंस भी रीको को मिला है, मेरे बच्चों को नहीं। रीको ने कहा, 'यदि आप दूसरी मिल लगाने को तैयार हों, तो वह साझेदारी करने को तैयार है।' सबको सरकार से २६ प्रतिशत सहयोग मिलता है। मेरे बच्चों को तो मात्र १० प्रतिशत

मिला है। यह तो इन बच्चों की हिम्मत समझिये कि फिर भी आगे बढ़े हैं।

माया: किंतु इस मामले में इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या थी, जब कि मामला उच्चन्यायालय में भी है?

सिंह: हां, मुकदमा चल रहा है। फैसला होने पर सचाई सामने आ जायेगी। राज्य में विपक्ष की अध्यक्षतावाली पीएसी इसकी जांच कर रही है और दिल्ली में उच्चन्यायालय जांच कर रहा है, इसीलिए मैंने आज तक कोई स्पष्टीकरण नही दिया। मुझे किसी तरह की चिंता या भय नहीं है। कारण, न तो कोई पक्षपात हुआ, न कोई घोटाला। कोई नहीं कह सकता कि गृहमंत्री के रूप में मैंने अपने बच्चों के लिए किसी को प्रभावित किया। मुझ पर आंच तो तब आयेगी, जब मैंने अपने पद का दुरूपयोग किया हो। और इस संबंध में मैंने न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार और न रीको से कोई संपर्क साधा है।

माया: पद के दुरूपयोग और घोटाले के बारे में अरुण नेहरू आप पर सीधे-सीधे आरोप लगाते हैं कि अकाल तख्त की मरम्मत का हिसाब-किताब आज तक आपने पेश नहीं किया। इसका भी जवाब आपने क्यों नहीं दिया?

सिंह: (कुछ उत्तेजित होकर) क्यों दूं जवाब? मेरी जवाबदेही अरुण नेहरू के प्रति नहीं है। मुझे काम सौंपा था, इंदिरा गांधी जी ने। उनके संतोष के मुताबिक काम हुआ। पैसे कहां से आये, किसने खर्चे, यह वे जानती थीं और मैं जानता हूं। उसका पूरा हिसाब-किताब उनके पास था।

माया: अरुण नेहरू और आपके एक समय में बहुत मधुर संबंध थे, किंतु आज पैदा हुई कटुता का कारण क्या यह है कि श्री नेहरू कांग्रेस के बाहर हैं या वे यह समझते हैं कि आपने उन्हें कांग्रेस से बाहर कराया है?

सिंह: अरुण नेहरू के साथ सभी कांग्रेसियों के अच्छे ताल्लुकात थे। पूरी पार्टी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। आम धारणा यह हो गयी थी कि सरकार अथवा पार्टी की बात करनी है, तो इन्हीं के साथ करनी होगी। पर यह सरासर झूठ है कि मैं उन्हें 'सर' कहता था। मैं सबको अदब के साथ बुलाता हूं। मीठा बोलता हूं। अरुण नेहरू की तरह 'ऐ', 'ओय' नहीं कहता। उनकी स्टाइल ही ऐसी थी कि वह कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को 'ऐ', 'ओय' कहते थे, मुख्यमंत्रियों को दरवाजे पर खड़ा रखते थे। विश्वनाथ तक को 'अरे विश्वनाथ' बुलाते थे। मेरी भिन्न स्टाइल का यह अर्थ नहीं कि मैं उनका गुलाम था।

माया: पंजाब समस्या के बारे में कहा जाता है कि न तो केंद्र हल चाहता है और न आप।

सिंह: बिलकुल गलत। पंजाब समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके बीच कोई व्यक्ति बाधक हो, यह संभव ही नहीं है। केंद्र पंजाब समस्या का हल चाहता है। इस समस्या के दो पहलू हैं। एक आतंकवाद पर काबू पाना, दूसरा, जो पंजाब की समस्या है, उसका समाधान करना। केंद्र के प्रयासों के बाद आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। समस्या के हल के लिए राजीव-लोंगोवाल करार ही एक आधार है, जिस पर फैसला हो सकता है, किंतु इसमें दिक्कत यह है कि पंजाब और हरियाणा के बीच समझौता नहीं हो रहा है। केंद्र के हाथ में सिर्फ इतना ही है कि वह दो पार्टियों को आपस में रजामंद कराये। पर जब तक वे रजामंद नहीं होतीं, तब तक केंद्र अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। केंद्र अपनी ओर से भरपूर मदद कर रहा है।

मेरा इसमें क्या दोष या हाथ रहा? कर्नाटक के मामले में स्वयं जनतादल के विभिन्न नेताओं के बयानों से ही यह स्पष्ट है कि बोम्मई सरकार अपने ही अंतर्विरोधों और आपसी कलह के कारण गिरी। रही मेरी भूमिका की बात, तो मैं शपथ सहित कह सकता हूं कि मैं देवगौड़ा से आज तक कभी नहीं मिला।

माया: कहा जाता है कि पंजाब के आतंकवादियों और जत्थेदारों से आपके संपर्क हैं।

सिंह: राजनीति के नीच लोग ही ऐसी अन्यायपूर्ण बात कर सकते हैं। मेरे आतंकवादियों से कैसे संबंध हो सकते हैं? मैं तो खुद उनका सबसे बड़ा शिकार हूं। चार लोग मेरे परिवार से मारे गये हैं। जिले-जिले में जाकर मैं आतंकवादियों का मुकाबला कर रहा हूं और लाखों के सामने जिस प्रकार उनकी धज्जियां उड़ा रहा हूं, अगर उनसे मेरे संबंध होते, तो क्या मैं ऐसा कर पाता? यदि इसमें लेशमात्र भी सचाई होती, तो गृहमंत्री की कुरसी पर मैं एक क्षण नहीं रह सकता था। हां, यह अवश्य है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाये, तो उससे कहलवाया जाये कि बूटा सिंह से उसका संबंध है। मैं तो ईश्वर का आभारी हूं कि उसने ऐसी साजिशों को नाकाम किया है। इसी तरह जत्थेदारों से यदि मेरे संबंध होते, तो उन्होंने मुझे भी ज्ञानी जैल सिंह की तरह माफ कर दिया होता।

माया: राजनीतिक आधार न होते हुए भी आपकी वर्तमान शक्ति का मूल स्रोत क्या है?

सिंह: क्या राजनीतिक आधार का अर्थ चार विधायक-सांसदों के आगे-पीछे होने से होता है? मेरी देश के प्रति निष्ठा है, सेवा की भावना है। मैंने पिछले २५ साल से देशसेवा की है। क्या इसका कोई मूल्य नहीं है? पूरा देश मेरा आधार है।

माया: अधिकांश लोग गांधी परिवार से आपकी निकटता को ही आपकी शक्ति का मूलाधार मानते हैं।

सिंह: मैं हमेशा प्रधानमंत्रीजी (राजीव गांधी) और श्रीमती गांधीजी का शुक्रगुजार रहूंगा कि मुझ पर कृपा कर सेवा का मौका दिया। शायद मैं इसके काबिल भी नहीं था। यह परिवार देश की एकता-अखंडता का प्रतीक है। इसीलिए मेरी इनके प्रति पूर्ण निष्ठा है। इनके हर आदेश का पालन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

माया: कहा जाता है कि इनके आदेश के पालन के लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाने में हिचकिचाते नहीं।

सिंह: यह सही नहीं। यह सच है कि मुझे जो भी काम सौंपा जाता है, उसे मैं पूरी निष्ठा व निर्भयता से क्रियान्वित करता हूं। यहां तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। पर न मुझे गलत आदेश मिलते हैं, न गलत काम करता हूं।

—रंजना कक्कड़,

क्या साखर लाबी के दिन लद गये?

गन्ना उत्पादक किसानों से विभिन्न ट्रस्टों के नाम पर चीनी मिलों के संचालकों द्वारा अनिवार्य रूप से वसूले जा रहे धन के खिलाफ आवाज उठाकर पूर्व सहकार मंत्री यशवंत राव मोहिते ने न केवल कृष्णा साखर (चीनी) कारखाने के संचालक मंडल के चुनाव में संपूर्ण विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने इसी तरह महाराष्ट्र की अन्य चीनी मिलों पर भी कब्जा करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कैसी हलचल मची हुई है?

दि सांगली जिल्हा कामगार को-ऑपरेटिव्ह ... लि. मुंबई
वी वार्षिक सर्वसाधारण

पोषण या शोषण? : सांगली कामगार इकाई की सभा में शालिनी पाटील

"महाराष्ट्र सरकार को अब जल्दी ही यह फैसला करना होगा कि उसके हित गन्ना उत्पादकों और किसानों से जुड़े हैं या साखर (चीनी) सामंतों से।" यह टिप्पणी है, राज्य के पूर्व सहकार मंत्री यशवंतराव मोहिते की, जिन्होंने एशिया के सबसे बड़े सहकारी चीनी कारखानों में से एक, कृष्णा साखर कारखाने (सातारा) के प्रबंधक बोर्ड की २१ में से २० सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जबर्दस्त गहमागहमीवाला यह चुनाव २ मई को हुआ था, जिसके नतीजे ४ मई को घोषित किये गये। पांच वर्षों के लिए यह चुनाव अगले कुछ हफ्तों में पश्चिमी महाराष्ट्र के दस और बड़े सहकारी चीनी कारखानों में भी होने हैं और विश्लेषणकर्ताओं के अनुसार इन चुनावों पर कृष्णा सहकारी कारखाने के चुनाव-परिणामों का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ना है, जिससे तमाम कारखानों के सुरक्षित निदेशक मंडलों को कुरसी खाली करनी पड़ सकती है।

चुनाव का मतलब: कृष्णा सहकारी साखर कारखाने के प्रबंध निदेशक मंडल का यह चुनाव गन्ना किसानों (जिनका नेतृत्व मोहिते करते रहे हैं) और कारखाने के चेयरमैन जयंतीराव भोसले लाबी के बीच निर्णायक युद्ध था। भोसले और मोहिते दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किये थे। मोहिते का आरोप था, "भोसले ने कारखाने के किसान सदस्यों के भुगतान से करोड़ों की रकम काटकर निजी पूंजी (ट्रस्ट) बनाने और अपनी राजनीतिक छवि निखारने में लगायी है," और मांग थी, "इन निजी ट्रस्टों को सरकार सार्वजनिक ट्रस्टों में तब्दील कराये।" दूसरी ओर क्षेत्र के विकास का श्रेय स्वयं लेनेवाले भोसले अपने अवकाश ग्रहण के बाद अपने पुत्र सुरेश को कारखाने का चेयरमैन बनाने में सारी शक्ति लगाये हुए थे। यशवंतराव सहकारी और शेतकरी सहकारी चीनी कारखानों के प्रबंधक, भोसले का समर्थन और मोहिते का विरोध कर रहे थे।

विवादास्पद कृष्णा सहकारी चीनी कारखाने और उसके प्रबंध का मुद्दा राज्य विधानसभा के प्रायः प्रत्येक सत्र में खुलकर उठाया जाता रहा है। पूर्व सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते कारखाने के प्रबंधकों के कथित भ्रष्टाचार को लेकर पिछले दो सालों से आंदोलन चलाते रहे हैं। एनडी पाटील (पीडब्ल्यूपी विधायक) तो इसी मुद्दे पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अनशन कर बैठे थे।

इस चुनाव का मुख्य मुद्दा था, "चीनी कारखानों द्वारा चलाये जा रहे ट्रस्ट और ट्रस्टों के लिए गन्ना किसानों के भुगतान से की गयी कटौती।" इसमें भोसले की हार का मतलब है, गन्ना किसानों और सहकारी क्षेत्र पर चीनी लाबी के वर्चस्व का खातमा।

कटौती का इतिहास: राज्य के ९१ में से करीब २० चीनी कारखाने गन्ना किसानों के भुगतान से सीधे धन काटते रहे हैं, कारखानों के चेयरमैनों के निजी ट्रस्टों के लिए। इन ट्रस्टों की राशि करीब ३ अरब रु० की हो गयी है। १९७९ में प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा शासन के दौरान, जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे, सहकार मंत्री एनडी पाटील ने एक निर्देश जारी कर इस तरह की कटौती पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन वसंत दादा पाटील के सत्ता में आते ही स्थिति पुनः पूर्ववत हो गयी। इसके बाद एनडी पाटील इस कटौती के खिलाफ ७ साल तक संघर्ष करते रहे और जब एसबी चह्वाण मुख्यमंत्री बने तब जाकर कृष्णा चीनी कारखाने के इस गोरखधंधे के प्रति सरकार ने सख्त रुख अपनाया। २४ अप्रैल, १९८७ को चीनी निदेशक सुधाकर जोशी ने निर्देश जारी किया, जिसके तहत किसानों से मंजूरी लिए बगैर उनकी रकम काटने पर रोक लग गयी। लेकिन कृष्णा कारखाने ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया—इस दलील पर कि सरकार जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुन लेती, तब तक इस बारे में अपना अंतिम निर्णय नहीं दे सकती। गत वर्ष १० मार्च को तत्कालीन सहकार एवं राजस्व मंत्री विलासराव देशमुख ने दोनों पक्षों से बातचीत के बाद यह कटौती रोकने के सरकारी फैसले को फिर दुहराया। लेकिन इस फैसले से कृष्णा कारखाने को चार माह बाद ४ जुलाई को अवगत कराया गया और इसी समय सरकार बदल गयी।

कारखाने के प्रबंधकों का दावा है कि यह कटौती किसानों की सहमति और सहकारी समिति की आमसभा की मंजूरी से की गयी है, पर यह दलील भ्रामक है। दरअसल, किसानों के लिए हां करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि नहर के पानी, बिजली, खाद और बैंक के ऋण के लिए वे पूरी तरह कारखानों की कृपा पर ही निर्भर

हैं। कारण, सहकारी बैंक बोर्डों में भोसले के रिश्तेदारों का ही बोलबाला है। खरीद के अनुबंधपत्र में ही यह शर्त (नं० १२) दर्ज है कि 'आखिरी भुगतान' से रकम काटकर ट्रस्टों को दान-स्वरूप दी जायेगी।'

कृष्णा फैक्टरी के प्रमुख पदों पर भोसले ने अपने पुत्र, पुत्री और दामाद को भी बैठा रखा है। जहां वे स्वयं कृष्णा चैरीटेबल तथा शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, वहीं सुरेश ग्रामीण विकास ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इन तीनों के नियंत्रण में ३० करोड रुपए हैं। जबकि इनकी पूंजीगत परिसंपत्तियां ६० करोड़ रु० की हैं। भोसले ने स्वयं को तो जीवन भर के लिए इन ट्रस्टों का चेयरमैन नियुक्त कर ही लिया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया।

चीनी की कडुवाहट : महाराष्ट्र की राजनीति में सत्तारूढ दल के लिए लंबे अरसे से मिठास घोलते आ रहे साखर (चीनी) कारखानों की असली तासीर कितनी कडुवी और दमघोंटू है, यह भेद अब खुलने लगा है। गन्ना किसानों के शोषण से एकत्र करोड़ों रु० के घालमेल का जिक्र करते हुए जहां राज्य के लोग इन कारखानों को 'नरक राज' की संज्ञा दे रहे हैं, वहीं घोटालों का जवाब देते-देते राज्य सरकार की नाक में दम आ गया है। चूंकि,यह सारा खेल जनता के खून-पसीने की रकम से खेला जाता रहा, इसलिए शिकायतें पहले भी होती थीं। लेकिन तब इन सहकारी साखर कारखानों के कर्ताधर्ता इसे कारखानों का निजी मामला कहकर और जनता पर धौंस जमाकर छुट्टी पा जाते रहे। साखर कारखानों के चुनाव में करोड़ों रु० फूक दिये जाते थे, लेकिन इस बात की भनक तक नहीं मिलती थी कि यह रकम आयी कहां से। जबकि हर किसान को मिलनेवाली कीमत में से प्रति टन गन्ने पर एक रुपया काटा जाता रहा। घोटाले ज्यादा हुए और शोर-शराबे मचे, तो सरकार जांच का ऐलान कर देती। बात ठंडी पड़ते ही जांच रफादफा कर दी जाती। लेकिन ज़ब कारखाने राज्य सरकार की ही भारी-भरकम राशि दबाकर बैठ जाये तो? शायद यह संगीन बात भी आयी-गयी हो जाती—अगर साखर कारखानों पर वर्चस्व के लिए कांग्रेस-इ में दो खेमें नहीं बन जाते।

जानकार सूत्रों के अनुसार चीनी कारखानों ने सरकारी योजनाओं के नाम पर २५ करोड़ रु० वसूले, किंतु वह रकम सरकार को दी ही नहीं गयी। करीब ७५ कारखानों में हर किसान से फी टन गन्ने पर एक रुपए के हिसाब से अल्पबचत की रकम काटी गयी। तर्क यह था कि किसान को मिलनेवाले हजारों रु० से मात्र कुछ सौ रु० अल्पबचत में डाले गये हैं, इससे एक ओर सरकार का खजाना भरेगा, तो दूसरी ओर किसान को भी जरूरत पड़ने पर एकमुश्त रकम मिल सकेगी। लेकिन वास्तव में हुआ क्या?

बताया जाता है कि चीनी कारखानेदार सारी रकम पचा गये। कुल १६ करोड़ ७८ लाख रु० से ज्यादा की धनराशि अल्पबचत के नाम पर

अमानत में खयानत : शरद पवार

एक साल के
अनुभव से पवार समझ गये हैं कि
ऐन चुनाव के मौके पर
चीनी लाबी को नाखुश करना ठीक
नहीं होगा।

साक्षात्कार/ अभय सिंह भोसले

आदेश जारी हो गये हैं

महाराष्ट्र के सहकार मंत्री अभय सिंह भोसले यह तो मानते हैं कि सहकारी सांखर (चीनी) कारखानों में गन्ना किसानों को मिलनेवाले भुगतान में की गयी कटौती में गोलमाल हुआ है, परंतु वे इस बात को कबूल नहीं करते कि सरकार 'लाचार तमाशबीन' बनी रही है। प्रस्तुत हैं, उनसे 'माया' की बातचीत के अंश :

माया : ***दोषी सहकारी चीनी कारखानों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गयी?***

भोसले : *यह सोचना कतई गलत है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। जिन कारखानों ने किसानों से काटी गयी रकम जमा नहीं की, उन्हें इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। २५ अप्रैल '८६ को राज्य के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को आदेश दे दिये गये हैं कि बकाया रकम तत्काल संबंधित अधिकारी को सौंप दी जाये।*

माया : ***कार्रवाई में किस-किस मद को शामिल किया गया है?***

भोसले : *मुख्यमंत्री निधि, बेघर (घरकुल) योजना निधि, दुष्काल निवारण, अल्पबचत तथा यशवंत राव चह्वाण प्रतिष्ठान-इन पांच मदों में की गयी कटौती के बारे में ये आदेश जारी किये गये। साथ में बकाया रकम की सूची भी उन्हें भेज दी गयी हैं। इनमें से यशवंत राव प्रतिष्ठान सरकारी संस्थान नहीं है। आदेश पर जल्दी अमल कराने के इरादे से निर्देश जारी किये गये कि सहकारी बैंकों को तुरंत मुख्यमंत्री निधि, व दुष्काल निवारण के विवरण भेजे जायें। यह काम अब सहकारी कारखानों तथा संचालक चीनी निदेशालय को दिया जायेगा।*

माया : ***क्या आप समझते हैं कि आदेश पर अमल होगा?***

भोसले : *आप यह क्यों सोचते हैं कि सरकारी निर्देशों पर अमल नहीं होगा? फिर भी चेतावनी दी गयी है कि यदि आदेशों का पूरा क्रियान्वयन कर सूचना नहीं दी गयी, तो सहकारी कानून की धारा ७६ (अ) के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।*

—बंबई ब्यूरो

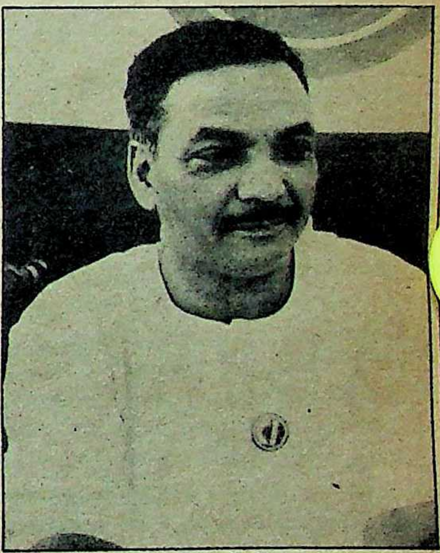

चीनी की मुस्कान : शरद जोशी

घोटाले ज्यादा
हुए और शोर-शराबे मचे, तो सरकार
जांच का ऐलान कर
देती। बात ठंडी पड़ते ही जांच
रफादफा कर दी जाती।

कारखानों ने दबाये रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री शरद पवार उन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और कहा करते थे कि यह 'अमानत' में 'खयानत' है। १६ जुलाई, '८८ को बहैसियत मुख्यमंत्री भी, उन्होंने आंखें तरेर कर कहा था कि अपराधी कारखानों के खिलाफ फौजदारी मुकदमे चलाये जाने चाहिए। उस समय वे भूल गये थे कि अल्पबचत के मद में एक करोड़ ३१ लाख ६१ हजार ८ सौ रु० पंचगंगा कारखाने ने काटे जिसके सर्वेसर्वा पूर्व मंत्री रत्नाप्पा कुंभार हैं। पहले नंबर पर था—सांगली का शेतकरी कारखाना जो वसंत दादा पाटील का खुद का था। वहां जमा किये गये एक करोड़ ३५ लाख ८७ हजार ८७० रुपए डाकघर या अल्पबचत विभाग को नहीं दिये गये।

साल भर बीत जाने के बाद पूछताछ शुरू हुई। शेतकरी (किसान) कामगार पार्टी के प्रो० नारायण ज्ञानदेव पाटील ने धरना दिया। महाराष्ट्र के सहकार मंत्री और कारखानेदार अभय सिंह भोसले ने वादा किया कि यह रकम कारखाने से वसूल की जायेगी। उनका दावा था कि कुल १४ करोड़ १६ लाख ७० हजार रु० किसानों से काटे गये और अब तक १३ करोड़ ४२ लाख रु० जमा किये जा चुके हैं।

किसने, कितना जमा किया ?

कारखाना	अल्पबचत	यशवंत राव प्रतिष्ठान	बेघर (घरकुल) योजना
शेतकरी (सांगली)	१,३५,८७,८७०	८,१६,०००	२४,३६,०००
पंचगंगा (कोल्हापुर)	१,३१,६१,८००	८,४१,०००	२३,१३,०००
वारणा (कोल्हापुर)	३३,८८,६६१	४,३०,०००	१८,८२,०००
कृष्णा (सातारा)	२८,८२,०००	७,५१,०००	२६,४६,०००
अजिंक्यतारा (सातारा)	६,४२,०००	१,५६,०००	जानकारी नहीं
कोपराराव	१६,५५,०००	३,०४,०००	७,८४,०००

इनमें से सभी के खिलाफ समय-समय पर गंभीर शिकायतें आयीं, कुछ मामले अदालत में गये। कुछ की सरकार ने जांच की। ये सभी बड़े छह कारखाने चीनी सहकारिता की दादागिरी तथा नेतृत्व के नमूने हैं। कई बड़े लोग उनसे जुड़े हैं।

कटौती के मद: किंतु यह कटौती सिर्फ अल्पबचत के मद में ही नहीं की गयी। कारखानों में 'मुख्यमंत्री निधि' के नाम पर हर टन गन्ने पर ५० पैसे काटे गये। प्रो० पाटील ने 'माया' को बताया कि १९८६-८७ में करीब ४.५ करोड़ रु० इस मद में काटे गये। उसी दौरान सूखा राहत के लिए हर टन पर दो रुपए के हिसाब से कटौती की गयी। सरकार यह तो मानती है कि इस तरह की कटौती प्रायः सभी कारखानों में की गयी, परंतु उसे यह नहीं मालूम कि कितने करोड़ रुपए वसूल किये गये।

सहकार मंत्री भोसले मानते हैं कि चीनी कारखानों को हर टन गन्ने के पीछे ५० पैसे काटने की इजाजत दी गयी, ताकि वे बेघरों को घर बनाकर दे सकें। इस 'घरकुल योजना' में ४ करोड़ ८४ लाख रु० जमा हुए। चीनी कारखानों के संचालकों से जब अप्रैल '८९ में पूछताछ की गयी, तो सबका एक ही जवाब था, "जमीन नहीं मिली, इसलिए बेघरों के लिए घर नहीं बनाये जा सके।"

इस सरकारी कटौती के अलावा भी एक कटौती की गयी। भारत के पूर्व रक्षामंत्री तथा नवीनीकृत महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चह्वाण जो मुख्यमत्री शरद पवार के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, का स्मारक बनाने के लिए (स्व०) वसंत दादा पाटील और शरद पवार की अगुवाई में एक समिति बनी। उनकी पहल पर ९१ में से करीब ५० कारखानों में प्रति टन एक रुपए कटौती शुरू की गयी। पंचगंगा कारखाने (कोल्हापुर) ने ८ लाख ४१ हजार और शेतकरी (सांगली) ने ८ लाख १६ हजार रु० काट लिये। यह बात सन १९८४-८५ की है। १९८९ में सरकार बतलाती है कि एक करोड़ ७३ लाख ५९ हजार रु० स्मारक समिति के कोष में जमा किये गये थे।

यशवंत राव का स्मारक बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने १९८९-९० के बजट में ५० लाख रुपए का प्रावधान किया। यह रकम स्मारक समिति को देने के लिए कागजात तैयार कर लिये गये। किंतु कारखानों में कटौती के बाद जमा रकम में से इतने हंगामे और शोर के बावजूद ३३ लाख रु० का पता नहीं है।

सरकार की लाचारी: इस 'दुर्विनियोग' के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का सुझाव देनेवाले मुख्यमंत्री पवार 'माया' को बताते हैं, "मैंने पूरे मामले की छानबीन की है। बकाया रकम जमा करने के कड़े आदेश जारी किये गये हैं। कुछ कारखाने ऐसे भी हैं, जिनके पास कर्मचारियों का वेतन चुकाने के लिए पैसे तक नहीं हैं। ऐसे कारखानों पर जोर-जबर्दस्ती करने से क्या मिलेगा ?"

इस सवाल का सबब क्या है ? साखर लाबी के सूत्र बताते हैं, "एक साल के अनुभव से पवार समझ गये हैं कि ऐन चुनाव के मौके पर चीनी लाबी को नाखुश करना ठीक नहीं होगा। ऐसे ही वसंत दादा पाटील की डांट से सहम कर इन्होंने कृष्णा सहकारी कारखाने की जांच ठंडे बस्ते में डालने का फरमान जारी किया था। इस पर अमल के पहले ही दादा पाटील गुजर गये।

चीनी कारखानों को विशेष दर्जा देने का विरोध शुरू हो गया है। यहां तक कि ८ अप्रैल को महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के सम्मेलन में इस आशय का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। युवा इंका अध्यक्ष अविनाश पांडे ने 'माया' को बताया, "प्रस्ताव में साफ शब्दों में कहा गया है कि चीनी कारखानों के साथ ही खेती पर आधारित अन्य कारखानों को संरक्षण दिया जाये। इसके साथ ही अक्षम चीनी कारखानों को सक्षम बनाने के लिए कदम उठाये जायें।" सत्ता दल की राजनीति में चीनी कारखानेदारी किस हद तक घुसी है, इसका पता इसी बात से लगता है कि देहाती इलाकों से जीतकर आया हर मंत्री किसी-न-किसी कारखाने से जुड़ा हुआ है। यहां तक कि हर विधायक तथा युवा नेता इन दिनों सहकारी कारखानों के चुनाव में सक्रिय है। साखर कारखानों पर वर्चस्व की इस होड़ से दिल्ली भी परेशानी में है।

विद्रोह की जीत: पूर्व सहकार मंत्री यशवंत राव मोहिते पर शक किया जाता रहा है कि वे महाराष्ट्र में ४० वर्षों के सहकारी आंदोलन की सकारात्मक उपलब्धियों पर पानी फेर देने के लिए कमर कस चुके हैं। जवाब में मोहिते कहते हैं, "१९७८ के बाद जब-जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आयी और मुख्यमंत्री बदले गये, तब-तब सहकारी चीनी कारखानों में गलत प्रवृत्तियां घुसती-बढ़ती रहीं और चीनी लाबी खुद को 'सरकार निर्माता' मानने लगी। पिछले दस सालों में सहकारी समितियां समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भूलकर भ्रष्टाचार को समर्पित हो गयीं। सहकारिता विभाग सोता रहा। राज्य सरकार 'लाचार तमाशबीन' बनी रही। गन्ना किसानों का शोषण बढ़ता गया।"

राज्य सरकार में २० वर्षों तक मंत्री रहने के बाद चीनी कारखानों के खिलाफ गन्ना किसानों के विद्रोह का नेतृत्व करनेवाले मोहिते आगे कहते हैं, "कृष्णा कारखाने के चुनाव ने दिखा दिया है कि हवा का रुख क्या है और अनीति-अन्याय के मारे किसानों में किस हद तक जागरूकता आ गयी है। इन चीनी कारखानों के 'वंशगत और बंधु-बांधव शासन' की समाप्ति का समय आ गया है और केवल स्वच्छ पेशेवाली व्यवस्था ही इस बीमारी का इलाज कर सकती है।" क्या महाराष्ट्र सरकार और चीनी लाबी में मोहिते के दावे को काटने का दम है ?

—बंबई ब्यूरो के साथ वशिष्ठ

नकली दवाओं का पनपता कारोबार

blow up
WEL PRO
LIQUID FOOD CONCENTRATE FORTIFIED WITH VITAMINS & IRON
Speed up
Vital
HIMPRO
LIQUID FOOD CONCENTRATE FORTIFIED WITH VITAMINS & IORNS

दवा या रंगीन पानी: कुछ दवाओं के रैपर

राजस्थान की सरकारी औषधि निर्माता संस्था की दवाएं ही जब अशुद्ध साबित हों और राजकीय प्रयोगशाला नाकारा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश में नकली दवाओं की बाढ़ न आये। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए और राजस्थानवासी दवा के नाम पर क्या पी रहे हैं?

राजकीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर

बेकार: राजकीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

आजकल राजस्थान में ऐन राजधानी जयपुर में दवा के नाम पर खुलेआम रंगीन पानी बिक रहा है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में दवाओं की शुद्धता और गुणवत्ता जांचने का काम रामभरोसे छोड़ दिया गया है। राज्य का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दूसरे कामों में इतना व्यस्त है कि औषधि नियंत्रण का काम यहां बेकार का काम समझा जाता है। अब तक सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं, उनसे साफ जाहिर है कि राज्य सरकार को इस बात की चिंता नहीं कि यहां बनने और बिकने वाली दवाएं मौत का पैगाम बांट रही हैं या अच्छी सेहत? सरकार की इसी बेफिक्री का लाभ उठाकर इस धंधे में लगे कुछ लोग घटिया और नकली दवाइयां बनाने का अपना कारोबार बढ़ाते जा रहे हैं और मालामाल हुए जा रहे हैं। कुछ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, कुछ दवा विक्रेताओं तथा कुछ चिकित्सकों की सहायता से इनका कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना फलफूल रहा है। हालत यह है कि राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के उत्पादन घटिया और जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रदेश में दवा के नाम पर शराब धड़ल्ले से बिक रही है। जिन मामलों में पकड़े जाने पर मुजरिमों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, उन मामलों को भी चुपचाप दाखिलदफ्तर किया जा रहा है। विडंबना ही कही जायेगी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सरकार हर साल अपने बजट का बहुत बड़ा भाग खर्च करती है, मगर औषधि नियंत्रण विभाग में सुधार के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं।

गड़बड़ी सरकारी उपक्रम में भी: राजस्थान में राज्य सरकार का एक उपक्रम है, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल)। सरकारी उपक्रम होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि इस उपक्रम में दवाइयां शुद्धता और गुणवत्ता को ध्यान में रख कर बनायी जाती होंगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आरडीपीएल से लिये गये डेक्सट्रोज इंजेक्शन के नमूनों को गाजियाबाद स्थित केंद्र सरकार की औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला 'फेल' करार कर चुकी है। इस उपक्रम में बननेवाले सोडियम क्लोराइड व डेक्सट्रोज इंजेक्शन (बोतल) के बैच नंबर आर २३९-बी तथा डेक्सट्रोज इंजेक्शन के बैच नंबर आर-२७१ के नमूने इस प्रयोगशाला में भेजे गये थे। दोनों दवाएं स्टरलिटी टैस्ट में अमान्य कर दी गयीं। इनमें माइक्रो आर्गंस मौजूद थे। चूंकि ये इंजेक्शन सीधे रक्त वाहिनियों में चढ़ाये जाते हैं, इसलिए इनमें माइक्रो आर्गंस का मौजूद रहना जानलेवा साबित हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार ऐसे ७-८ अन्य निर्माताओं के भी इसी तरह के उत्पादनों में ऐसी ही गड़बड़ियां पायी गयीं। अब सरकार के सामने संकट यह है कि चूंकि इसका स्वयं का उपक्रम घटिया उत्पादन कर रहा है, तो वह दूसरों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करे? शायद इसीलिए इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। बताया जाता है कि बाजार में बहुत सी ग्लूकोज की ऐसी बोतलें आ रही हैं, जिनकी प्रति बोतल कीमत १८ रुपए है, मगर उनमें १८ पैसे का भी ग्लूकोज नहीं होता सिवा पानी के। मरीजों की रगों में ऐसी बोतलों को चढ़ाने की क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार इस तरह के कई मामलों में प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खतरे के संकेत दिये गये थे, मगर उन पर अदालत में कार्यवाही करना तो दूर, उन्हें फाइल करने में ही अधिकारियों ने खैर समझी है। इसी प्रकार सरकारी खरीद में भी गड़बड़ी होने की बात सामने आयी है। सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार ने कोटा स्थित एक औषधि निर्माता से थाईइथाइलीन कार्बोमैजीन की गोलियां खरीदीं। इन गोलियों के नमूने औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला में भी भेजे गये। परीक्षण के बाद पता चला कि उसमें औषधि की मात्रा १०० के बजाय केवल ४६ प्रतिशत निकली, मगर सरकार ने निर्माता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

जयपुर स्थित जावा फार्मास्युटिकल्स एंड कास्मेटिक्स द्वारा निर्मित आंख की दवाई नियोजान में औषधि की मात्रा जरा भी नहीं पायी गयी। यह दवा आंख का इंफेक्शन बहुत बढ़ने पर काम आती है। जब दवा में वास्तविक औषधि का प्रतिशत बिलकुल नहीं होगा, तो वह बेकार है। राज्य के एक अन्य निर्माता ने भी इसी नाम से यह दवा बनायी। सूत्रों के अनुसार उसके पास यह दवा बनाने की अनुमति ही नहीं थी। इस दवा में भी औषधि की

मात्रा नगण्य पायी गयी। इसके बावजूद दोनों निर्माताओं के खिलाफ आज तक न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आये ३ साल से ज्यादा समय गुजर गया। जावा फार्मास्युटिकल्स (दूसरी फर्म) द्वारा निर्मित आंख की ही एक दवा 'साइक्लोडेक्स' को गाजियाबाद स्थित प्रयोगशाला ने 'फेल' करार कर दिया, क्योंकि उसमें जीवन रक्षक औषधि की मात्रा ४८.६५ प्रतिशत ही थी। इस मामले में भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस तरह के मामलों में कार्यवाही के नाम पर बस प्रशासनिक स्तर पर लीपापोती कर दी जाती है। उन्हें सजा के नाम पर ३ माह तक दवा का निर्माण न करने की केवल हिदायत भर दी जाती है। इस सजा की भी निर्माताओं को आदेश जारी होने से पहले जानकारी करा दी जाती है। निर्माता भी कुछ इतने चालाक हैं कि वे ३ माह की मांग के मुताबिक दवाएं पहले ही बनाकर स्टाक कर लेते हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इस तरह के मामलों में भारी सजा दी जा सकती है। प्रयोगशाला ने जिस किसी भी दवा को अवमानक घोषित किया है, उसके निर्माता के खिलाफ न्यायालय में कार्यवाही का स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम में है। परंतु राजस्थान में हो यह रहा है कि ऐसे निर्माताओं को केवल चेतावनी देकर, या कुछ समय के लिए दवा बनाने की अनुमति वापस लेकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्रयोगशाला की रिपोर्ट दाखिलदफ्तर कर दी जाती है। इस तरह की अवमानक दवाओं के मामले में अदालत ३ साल की कैद की सजा दे सकती है। सूत्रों के अनुसार जो दवाएं एकदम नकली घोषित कर दी जाती हैं, उनके निर्माताओं के खिलाफ भी सरकार अदालत में नहीं जाती। अधिनियम में इसे गैरजमानती अपराध माना गया है, मगर चालान ही पेश नहीं किया जाता है, तो जमानत होने-न-होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नकली दवाओं के मामले में तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, लेकिन पता नहीं किसके हित कहां जुड़ जाते हैं कि ऐसे मामले अदालत में जा ही नहीं पाते और मौत का व्यापार जारी रहता है। प्रयोगशाला जांच की जिन रिपोर्टों पर अदालती कार्यवाही को भारत सरकार की औषधि सलाहकार समिति ने जरूरी माना है, उनका विवरण सभी राज्य सरकारों को ४-५ वर्ष पूर्व भेजा जा चुका है, लेकिन राजस्थान में इसका पालन करना जरूरी नहीं समझा जाता। औषधि नियंत्रण विभाग में ढील का ही परिणाम है कि नकली और घटिया दवाएं बनाने में जयपुर अपना सानी नहीं रखता। यहां बननेवाली दवाएं राज्य के ग्रामीण इलाकों में तो जाती ही हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल तथा दक्षिणी राज्यों में भी धड़ल्ले से भेजी जाती हैं। जयपुर के साथ एक कलंक जुड़ चुका है जिसके कारण यहां के गिने-चुने अच्छे औषधि निर्माताओं को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मिलावट व नकल : सरकार की यह ढील उन लोगों के लिए वरदान बन गयी है, जो तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं—चाहे इसके लिए इंसानी जिंदगी को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। लचर नियम-कानूनों और इस ढील के कारण जयपुर में इन दिनों मिलावटी व बड़ी कंपनियों के ब्रांडों से मिलती-जुलती घटिया दवाएं धड़ल्ले से बनायी जा रही हैं। एक बड़ी कंपनी (ग्लैक्सो) के ग्लूकोज पाउडर के लोकप्रिय ब्रांड से मिलते-जुलते कई तरह के डिब्बे यहां हर दुकान पर रखे नजर आ जायेंगे। इन डिब्बों की शक्ल हूबहू बड़ी कंपनी के डिब्बे से मिलती है। बस नाम की स्पेलिंग में मामूली-सा अंतर होता है। ये डिब्बे तीन-चौथाई कीमत पर मिल जाते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल तथा उसके आसपास बनी डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं में प्रति दिन सैकड़ों लोग अपने रक्त की जांच कराते हैं। ज्यादातर मामलों में लोगों को पहले ग्लूकोज का एक पैकेट पानी में घोल कर पिलवाया जाता है। जानकार लोगों का दावा है कि अस्पताल के आसपास ग्लूकोज के मिलावटी पैकेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। सौ ग्राम के ग्लूकोज पैकेट थोक बाजार में १८ रुपए दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इस हिसाब से ग्लूकोज का एक डिब्बा थोक विक्रेता डेढ़ रुपए में बेचता है। यह कीमत साबित करती है कि ग्लूकोज पाउडर मिलावटी होता है। ग्लूकोज पाउडर के

दवा के नाम पर शराब

अप्रैल के पहले सप्ताह तक राजस्थान के कई शहरों में अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में ५० से ५६ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त द्रव धड़ल्ले से बिक रहा था। कहीं-कहीं तो ८६ से ९० प्रतिशत अल्कोहल वाली 'दवा' की बोतलें भी हजारों की तादाद में रोज बिक रही थीं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार रोज इन दवा की बोतलों से भरे ट्रक राजस्थान में आते और हाथों-हाथ खाली हो जाते। उस समय तक न तो राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चेता था और न आबकारी विभाग। सस्ते में तेज नशा करने वालों की तो जैसे मौज हो गयी थी। बाजार में 'वीक टिंचर जिंजर' (बीपी) नामक ऐसी दवा ५ से ६ रुपए प्रति शीशी (१८० मिली) के हिसाब से मिल रही थी, जिसमें ८६ से ९० प्रतिशत अल्कोहल होता है। अल्कोहल की इतनी मात्रा तो थ्री-एक्स रम में भी नहीं होती। कहते हैं कि जो एक बार इस टिंचर का स्वाद चख लेता है, उसे थ्री-एक्स रम भी बेकार लगने लगती हैं। इसी तरह ५० से ५६ प्रतिशत अल्कोहल वाली अंग्रेजी दवा अशोका लीक्विड (आईपी) तो खूब चली। कम और तेज नशा करनेवाले, दोनों तरह के लोग इसे पसंद करते हैं।

पता नहीं कब से यह दवा रूपी शराब यहां बिक रही थी। लेकिन मार्च का अंत आते-आते तो हद ही हो गयी। दवाइयों की दुकानों के अलावा परचून और पान की दुकानों पर भी यह शराब बिकने लगी। पिछड़े मोहल्लों तथा कच्ची बस्तियों में इनका प्रचलन तेजी से बढ़ गया। और किसी को चिंता होती या न होती, सबसे ज्यादा चिंता उन्हें होने लगी, जो शराब के ठेके चलाते हैं। वे हतप्रभ थे कि मार्च के आखिरी दिनों में जब शराब बहुत ज्यादा बिकती है, उस समय सारे शराबी कहां चले गये? जल्दी ही उन्हें पता लग गया कि वे कहां जाते हैं और क्या पीते हैं? बात अखबारों तक पहुंची। कुछ दिनों तक दवा के नाम पर शराब बिकने की खबर सुर्खियों में रही। प्रशासन चेता और धड़ाधड़ छापे मारे गये, नमूने लिये गये, बिलों की जांच की गयी। तब जाकर कहीं बिक्री कम हुई। शराब के ठेकेदारों ने चैन की सांस ली।

कहां से आती है यह शराब? : वैसे तो ये नशीली दवाएं काफी अरसे से राजस्थान में बिकती रही हैं, लेकिन शराब के रूप में उनका दुरुपयोग अचानक ही बढ़ा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसके लिए हरियाणा सरकार को प्रमुख रूप से जिम्मेदार ठहराते हैं। राजस्थान में आयुर्वेद के सहायक औषधि नियंत्रक ओम प्रकाश शर्मा बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने इस तरह की दवाइयां बनाने के लिए जी खोल कर लाइसेंस दिये हैं। करनाल, सोनीपत आदि जिलों में पचासों फैक्ट्रियां हैं। वहां इन दवा निर्माताओं से आबकारी शुल्क वसूला जाता है। निर्माताओं को अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों को प्रति बोतल एक निर्धारित राशि देनी पड़ती है। इसके बाद व्यवस्था ऐसी की गयी है कि यह दवा हरियाणा प्रांत में नहीं बिक सकती। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि शराब के ठेकेदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यहां से इसे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भेज दिया जाता है।

शर्मा का दावा है कि आयुर्वेद की जिस दवा का दुरुपयोग हो रहा है, वह है मृत संजीवनी सुरा। इसमें २४ से ४० प्रतिशत तक अल्कोहल होता है। राजस्थान में पिछले २-३ साल से इस दवा के उत्पादन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। पांच फरवरी '८८ के बाद किसी लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं किया गया। इस समय कुल १०

मामले में निर्माताओं को केवल रिपैकिंग लाइसेंस दिये जाते हैं। इस पाउडर का कोटा सरकार इन निर्माताओं को ग्लूकोज बैग के रूप में आवंटित करती है, जिसे ये लोग प्लास्टिक की थैलियों में भर कर डिब्बे में पैक करते हैं। ये बैग ५० किलोग्राम वजन के होते हैं और इसकी दर ६०० रुपए से भी ज्यादा ली जाती है। यानी निर्माताओं को यह ग्लूकोज १२ से १३ रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से मिलता है। जाहिर है १०० ग्राम ग्लूकोज के लिए उन्हें एक रुपया २० पैसे या एक रुपया तीस पैसे सरकार को देने पड़ते हैं। वे इस १०० ग्राम ग्लूकोज की थैली में, थैली को डिब्बों में और डिब्बों को कार्टून में पैक करते हैं। इस प्रक्रिया में एक डिब्बे की लागत करीब ५० पैसे बढ़ जाती है। मगर इसके बावजूद थोक विक्रेता १८ रुपए दर्जन में इसे बेचता है, जिसमें उसका खुद का मुनाफा भी शामिल है।

नकली ग्लूकोज कैसे बनता है?: खोजबीन करने पर मालूम पड़ा कि ग्लूकोज के इन डिब्बों में मिलावट की जाती है। चीनी को चक्कियों में महीन पिसवाया जाता है, उसमें असली ग्लूकोज पाउडर नाममात्र को मिलाया जाता है। दूसरी गड़बड़ी यह की जाती है कि १०० ग्राम के पैकेट में केवल ९० ग्राम ग्लूकोज पाउडर पैक किया जाता है। थैली और डिब्बे का वजन मिलाकर डिब्बा १०० ग्राम का बैठता है।

दवा का दूसरा धंधा जो जयपुर में कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है, वह है—प्रोटीन लिक्विड का धंधा। यह धंधा नियम-कानूनों की विसंगतियों के कारण फल-फूल रहा है। प्रोटीन लिक्विड को 'ड्रग' न मानकर 'फूड' माना जाता है। इसे बनाने के लिए औषधि नियंत्रक से ड्रग लायसेंस नही लेना पड़ता, बल्कि इसके लिए नगर परिषद फूड लाइसेंस देती है। मगर प्रोटीन लिक्विड के डिब्बे दवाओं की दुकानों पर धड़ल्ले से बिकते हैं। प्रोटीन लिक्विड के २०० मिली की बोतल का पैक ग्राहक को २६ रुपए में पड़ता है, जबकि थोक में वह पैक ५ रुपए प्रति डिब्बे की दर से सामान्यत: उपलब्ध है। इस पांच रुपए में एक रुपया ६० पैसे बोतल के तथा एक रुपया चालीस पैसे लेबल, पैकिंग आदि के शामिल हैं। थोक विक्रेता का मुनाफा निकाल दिया जाये, तो २०० मिली की बोतल में आनेवाला तथाकथित प्रोटीन लिक्विड एक रुपए का होता है। इस एक रुपए में प्रोटीन, विटामिन, चीनी सब कुछ होता है। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इस २६ रुपए वाले डिब्बे में जो मात्र एक रुपया कीमत का प्रोटीन लिक्विड है, वह शरीर के लिए कितना फायदेमंद होगा? चिकित्सकों की राय है कि इस २६ रुपए के डिब्बे को खरीदने के बजाय केवल २६ पैसे पौष्टिक आहार पर खर्च किये जायें, तो शरीर को इसके मुकाबले कई गुना फायदा पहुंचेगा। लेकिन कुछ चिकित्सक ही इस काले धंधे में सहभागी बने हुए हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार इन चिकित्सकों को मालूम होता है कि यह प्रोटीन लिक्विड बेकार है, लेकिन फिर भी वे उसे पर्ची पर लिखते हैं। सूत्रों का कहना है कि ग्राहक से जो २६ रुपए लिये जाते हैं, उसका एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा इन्हीं चिकित्सकों की जेब में कमीशन के रूप में जाता है। करीब ६ रुपए प्रति डिब्बा दुकानदार बचाता है।

प्रोटीन लिक्विड एक रुपए में २०० मिली कैसे मिलता है? यह आंखों में धूल झोंकने की कला का एक अनूठा उदाहरण है। डिब्बे पर जो रासायनिक संगठन लिखा जाताा है, उसके हिसाब से उसमें कोई मिलावट नहीं होती। सारा काम नियमों के तहत होता है। लेकिन यह रासायनिक मात्रा इस तरह लिखी जाती है कि पढ़े-लिखे लोग तक धोखा खा जाते हैं। प्रोटीन लिक्विड के रासायनिक सघटकों में प्रमुख तत्व है प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। पैक पर लिखा जाता है हर १५ मिली में ५०० मिग्रा प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट है। इसके आगे कोष्ठक में लिख दिया जाता है २० प्रतिशत यानी जो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट मिलाया जाता है, उसमें रसायन वास्तव में केवल २० प्रतिशत है। इस २० प्रतिशत शक्तिवाले रसायन का आधा ग्राम कितना फायदा करेगा, यह सोचने की बात है। २०० मिली की बोतल में करीब ७ ग्राम २० प्रतिशत शक्तिवाला प्रोटीन होगा। सौ प्रतिशत शक्ति होती, तो प्रोटीन डेढ़ ग्राम से ज्यादा नहीं होता, जबकि एक सामान्य आदमी को ५५ ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन जरूरत

उत्पादकों के पास इसका लाइसेंस है। उनमें से ३ मृत संजीवनी सुरा बना रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में बनी मृत संजीवनी सुरा दुकानों पर बहुत कम बिकती देखी गयी है। जबकि जानकार सूत्रों का कहना है कि राजस्थान के निर्माताओं ने भी मौका देखकर मृत संजीवनी सुरा का उत्पादन बढा दिया है। अब अप्रैल माह में पड़े छापों के बाद उन्हें उत्पादन कम करना पड़ा, क्योंकि खपत कहां हुई, यह बताना पड़ेगा। अंग्रेजी या आयुर्वेदिक दवा के रूप में उत्पादन के लाइसेंस के अलावा उत्पादकों को इन दवाओं के लिए आबकारी का लाइसेंस भी लेना पड़ता है, ताकि इनमें अल्कोहल का प्रतिशत नियंत्रित रहे। हाल के छापों के दौरान कई जगह इनके नमूने भी लिये गये हैं।

कौन-सी दवा में कितना नशा: इस समय चार दवाओं का दुरुपयोग शराब के रूप में किया जा रहा है। ये हैं वीक टिंचर जिंजर (बीपी), अशोका लिक्विड (आईपी), अश्वगंधा लिक्विड (आईपी) तथा मृत संजीवनी सुरा। ये चारों अपने नाम के कारण आयुर्वेदिक दवा होने का अहसास देती हैं, जबकि इनमें आयुर्वेदिक केवल मृत संजीवनी सुरा है। शेष तीनों दवाएं अंग्रेजी हैं। वीक टिंचर जिंजर में अल्कोहल ८६ से ९० प्रतिशत, अशोका लिक्विड में ५० से ५६ प्रतिशत, अश्वगंधा लिक्विड में ५० प्रतिशत तथा मृत संजीवनी सुरा में २४ से ४० प्रतिशत होता है। अंग्रेजी दवाओं में यह अल्कोहल ऊपर से मिलाया जाता है। मृत संजीवनी सुरा में यह दवा के आसवन के दौरान स्वत: पैदा होता है।

अंग्रेजी दवाएं वस्तुत: यूटेराइन टानिक हैं। प्राय: महिलाओं के प्रसव के बाद इन्हें दिया जाता है। महिलाओं को ये दवाएं एक बार में २ से ४ मिली दी जाती हैं, जबकि शराब के रूप में पीनेवाले एक दिन में २०० मिली तक पी जाते हैं। चिकित्सक बताते हैं कि जिस तादाद में ये दवाएं बिक रही हैं, पूरे देश की महिलाएं प्रसव के बाद इसे लें, तब भी उतनी दवा की खपत नहीं हो सकती। ये दवाएं डाक्टर की पर्ची पर ही बिक सकती हैं, मगर जयपुर में बिना पर्ची के आज भी ये दवाएं आराम से खरीदी जा सकती हैं। कुछ अरसे पहले 'मेंड्रेक्स' जैसी दवा भी इसी तरह बिका करती थी। उसका भी नशेबाजों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो सरकार ने उस पर रोक लगा दी। अगर इन दवाओं की बिक्री पर भी नियंत्रण नहीं किया गया, तो इनका भी वही हश्र होनेवाला है।

मृत संजीवनी सुरा आयुर्वेदिक औषधि है। इसे बनाने का तरीका भैषज्य रत्नावली ग्रंथ में दिया गया है। इसको बनाते समय गुड़ का आसवन विभिन्न औषधियों के साथ किया जाता है। ज्यादा ताप के कारण उसमें अल्कोहल उत्पन्न हो जाता है। जटिल होने के कारण इस तरीके को बहुत कम लोग काम में लाते हैं। ज्यादातर निर्माता अल्कोहल ऊपर से मिला देते हैं। इस दवा की २०० मिली की शीशी दस-बारह रुपए तक आराम से उपलब्ध है।

पता चला है कि आबकारी विभाग ने काफी पहले इन दवाओं के दुरुपयोग की आशका को देखते हुए सरकार से नये नियम बनाने का आग्रह किया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि इन दवाओं के आयात-निर्यात और बिक्री को मंजूरी देने का अधिकार इस विभाग को दिया जाये। लेकिन इस बारे में कोई निर्णय आज तक नहीं लिया गया।

अब तक इन दवाओं पर नाम मात्र का आबकारी शुल्क लगता था, जिसे एक अप्रैल से थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। अंग्रेजी दवाओं पर पहले ६ रुपए ६० पैसे प्रति लीटर तथा मृत संजीवनी सुरा पर ५२ रुपए ८० पैसे प्रति लीटर आबकारी शुल्क था, जिसे बढ़ाकर अब क्रमश: करीब २० रुपए और ८० रुपए कर दिया गया है। इसके बावजूद लोग ये 'दवाएं' खरीद रहे हैं। नशाखोरी बढ़ती जा रही है। 'यह तो दवाई है' कह कर नये पियक्कड़ इसे खूब खरीदते हैं। —भु०जै०

होती है, जो ऐसी ३६ बोतलों में भी नहीं मिलता। फिर प्रोटीन लिक्विड तो उन लोगों के लिए लिखा जाता है, जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत महसूस होती है। यह मंहगा 'मीठा पानी' जयपुर में आकर्षक डिब्बों में पैक किया जाता है। शहरों से ज्यादा इसकी खपत गांवों में है, जहां लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। राजस्थान के दूर-दराज के इलाकों के अलावा यह प्रोटीन लिक्विड बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में भी काफी मात्रा में यहां से भेजा जाता है। जयपुर का नाम असर डालनेवाला नहीं है, इसलिए निर्माता पैक पर जयपुर नहीं लिखते, बल्कि महल्ले का नाम लिख कर छोड़ देते हैं जैसे मालवीय नगर, शांति नगर। उसके नीचे बंबई का कोई पता लिख दिया जाता है। जयपुर का नाम होता भी है, तो छोटे अक्षरों में। उससे बड़े अक्षरों में बंबई लिखा होता है। सीधे-सादे ग्राहक कंपनी को बंबई की समझ कर धोखा खा जाते हैं। मजे की बात यह है कि राज्य कर्मचारियों को इन तथाकथित टानिकों के पैसे का पुनर्भरण भी हो जाता है, जिसका सीधा भार सरकारी कोष पर पड़ता है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के बहुत से कर्मचारियों को नियमों की विसंगतियों और इस कारोबार के लाभ की जानकारी है, इसलिए उन्होंने खुद ही प्रोटीन लिक्विड का कारोबार शुरू कर दिया है। फूड लाइसेंस के नियमों में प्रोटीन तत्व की शक्ति जांचने का प्रावधान नहीं है।

औषधि नियंत्रण का लचर ढांचा : राजस्थान में औषधि नियंत्रण विभाग जैसा कोई अलग संगठन नहीं है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक ही औषधि नियंत्रक भी हैं। उनके पास दूसरे कार्यों का ही इतना बोझ है कि वे औषधि नियंत्रण पर खास ध्यान दे नहीं पाते। उन्हें चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मलेरिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि कई काम देखने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक वे मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं। यहां तक कि 'माया' प्रतिनिधि औषधि नियंत्रण के बारे में उनसे बात करने के लिए उनके कार्यालय एक सप्ताह में सात बार गया मगर उनके निजी सहायक ने हमेशा ही यह जवाब दिया कि आज चार मीटिंग हैं, तो कल पांच।

भारत सरकार बार-बार इस बात पर जोर देती रही है कि हर राज्य में पृथक औषधि नियंत्रणालय होना चाहिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, प० बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि सभी राज्यों में औषधि नियंत्रक का पद अलग है। मगर राजस्थान सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने भी घाटा और नकली औषधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए अलग औषधि नियंत्रणालय की जरूरत बतायी है, लेकिन अभी तक तो इस दिशा में कोई काम हुआ नहीं। भारत सरकार की ओर से बनी 'हाथी कमेटी' ने भी इसी तरह का सुझाव १९७० में दिया था, मगर १९ साल तक उस पर अमल नहीं हुआ। भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। उसने औषधि नियंत्रक का पृथक पद सृजित करने के साथ यह भी सुझाव दिया था कि हर २५ दवा फैक्ट्रियों तथा हर सौ दवा की दुकानों पर कम-से-कम एक औषधि निरीक्षक होना चाहिए। आज राजस्थान में करीब १५० दवा की छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां तथा करीब ७००० दुकानें हैं। इसी तरह १०० लोगों को दवा उत्पादन का लोन लाइसेंस दिया गया है। इन पर टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार ७८ औषधि निरीक्षक होने चाहिए। लेकिन आज राजस्थान में औषधि निरीक्षकों के सिर्फ २९ पद हैं, जिनमें से ५ पद पिछले ढाई साल से खाली पड़े हैं। राजस्थान में औषधि नियंत्रण शाखा १९७३ में खुली। लेकिन १६ वर्ष बीत जाने के बावजूद इस विभाग के निरीक्षकों व अधिकारियों के लिए सेवा-नियम नहीं बने हैं। दो पद सहायक औषधि नियंत्रकों के हैं, मगर उनका काम भी निरीक्षकों को ही देखना पड़ता है। निरीक्षकों को दूर-दूर तक अपनी पदोन्नति की उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसे में भ्रष्टाचार पनपना स्वाभाविक लगता है।

बेखबर ? : स्वास्थ्य मंत्री रघुनाथ विश्नोई

राजस्थान में होने को एक औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भी है, लेकिन कर्मचारियों और उपकरणों के अभाव में वह नाम मात्र को हर काम कर रही है। बंबई में कुछ वर्ष पहले जेजे अस्पताल में ग्लीसरीन कांड हुआ था, जिसमें कुछ लोग मारे भी गये थे। उसकी जांच के लिए नियुक्त किये गये लेंटिन कमीशन ने औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला को बहुत मजबूत करने की सिफारिश की थी। साथ ही यह भी कहा था कि ऐसा करने में धनाभाव आड़े नहीं आना चाहिए। मगर उस रिपोर्ट से शायद राजस्थान सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। भारत सरकार ने १९७५ में १० लाख रुपए का अनुदान देकर जयपुर में औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला का निर्माण कराया था। मगर इस भवन में १३ वर्ष बाद प्रयोगशाला को स्थानांतरित किया गया। आज भी इस भवन के बड़े हिस्से में स्वास्थ्य विभाग का स्टोर है तथा प्रयोगशाला को थोड़ी-सी जगह ही दी गयी है।

इस प्रयोगशाला में सहायक औषधि विश्लेषक का पद पिछले १० वर्ष से खाली पड़ा है। सिर्फ एक औषधि विश्लेषक है जो वर्ष में ४००-५०० नमूनों से ज्यादा की जांच नहीं कर पाता। शेष नमूनों को जांच के लिए भारत सरकार की कलकत्ता या गाजियाबाद स्थित प्रयोगशाला में भेजना पड़ता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन प्रयोगशालाओं से कई बार तो रिपोर्ट नमूनों के भेजने के २-३ वर्षों बाद आती है। तब तक वह दवा 'एक्सपायर' हो चुकी होती है। अगर रिपोर्ट में दवा नकली भी घोषित कर दी जाये, तो तब तक काफी देर हो चुकी होती है। विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि दवा बिकने से पहले ही कार्यवाही हो सके, इसके लिए रिपोर्ट जल्द-से-जल्द आनी चाहिए। प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर ही राज्य की प्रयोगशाला में एक अप्रैल, १९८८ से एक औषधि विश्लेषक, एक सहायक औषधि विश्लेषक तथा ४ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों के पद सृजित किये गये, मगर उन्हें विभाग ने आज तक नहीं भरा।

इतने कम औषधि निरीक्षक ठीक तरह से हर फैक्ट्री व हर दुकान से नमूने नहीं ले पाते। नियमानुसार उन्हें महीने में ५ नमूने लेने चाहिए, मगर वे कार्य का दबाव अधिक होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। नमूने के लिए जाते हैं, तो टैस्टिंग की सुविधा नहीं है। टैस्टिंग हो जाये और रिपोर्ट में नमूने को 'फेल' करार दे दिया जाये, तो कार्यवाही नहीं होती। कुछ समय के लिए औषधि बनाने का अधिकार वापस ले लिया जाता है। कई बार लाइसेंस रद्द कर दिये जाते हैं, मगर निर्माता दूसरे नामों से लाइसेंस ले लेते हैं। कुछ निरीक्षकों पर औषधि निर्माताओं से मिलीभगत का आरोप भी लगाया जाता है। अधिकारियों तक को पता होता है कि नकली व घटिया दवाएं बन व बिक रही हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। रिपोर्ट खिलाफ आने पर मामले को अदालत में ले जाने के बजाय लीपापोती कर दी जाती है। दुकानों की यह हालत है कि नियमों को ताक पर रखकर बिना डाक्टर की पर्ची के कोई भी दवा ज्यादातर दुकानदार दे देते हैं। जयपुर की करीब पचास प्रतिशत दुकानों पर फार्मेसिस्ट नहीं बैठते। नाममात्र के लिए उनका नाम दुकानों पर चल रहा है। ये बातें निरीक्षक जानते हैं, परंतु वे कोई कार्रवाई नहीं करते। नकली और घटिया दवा का हौवा ऐसा बना होता है कि लोगों का विश्वास दवाओं से उठने लगा है। लेकिन वे दवा के नाम पर रंगीन पानी पीते रहने के लिए अभिशप्त हैं।

—भुवनेश जैन

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

किसका कल्याण कर रहा है?

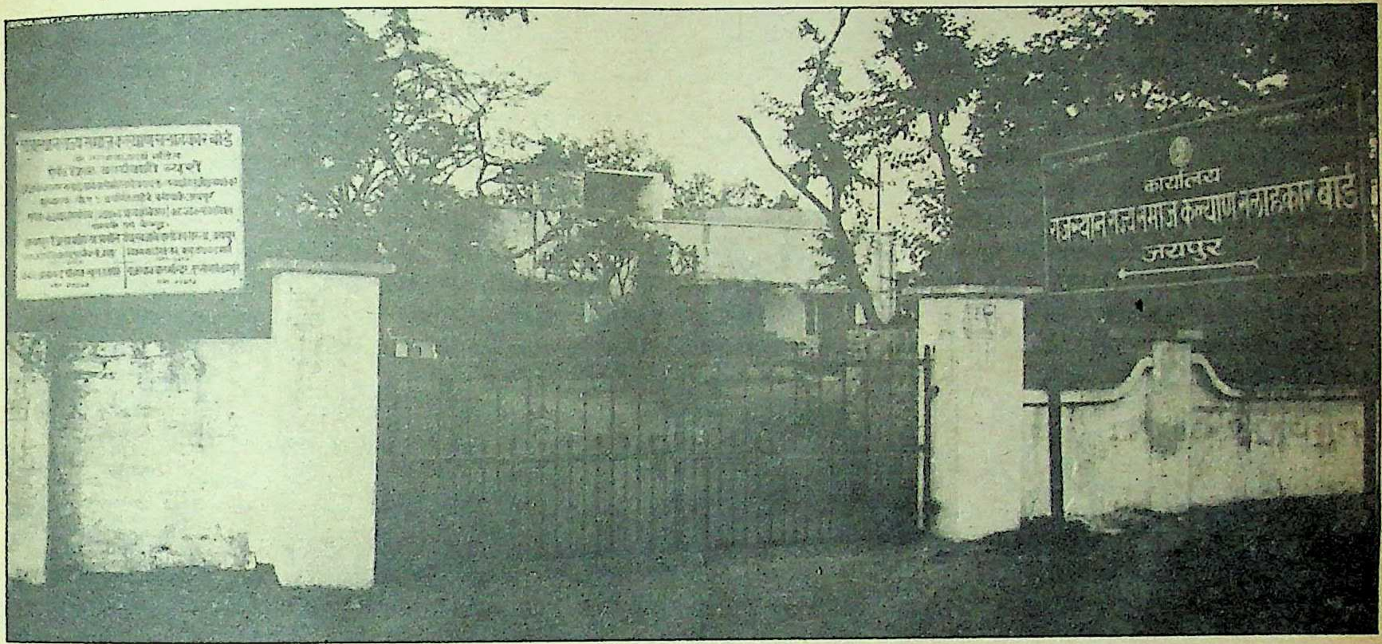

ईमानदार संस्थाओं के लिए द्वार बंद: बोर्ड का दफ्तर

दीन-हीन और निर्बल वर्गों, खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण और उत्थान के नाम पर सरकारी खजाने से अरबों रुपए की राशि निकाली जाती है। सरकार के प्रचार माध्यम इन कल्याण-योजनाओं की सफलता को अकसर बखानते रहते हैं। पर जिनके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च-होती है, उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। आखिर कहां चली जाती है यह रकम?

सरकार कल्याण-कार्यक्रमों पर जितनी बड़ी रकम खर्च कर रही है, उसे जानकर आप दंग रह जायेंगे। जिन 'गरीब व कमजोर लोगों के कल्याण' के लिए अरबों रु० खर्च हो रहे हैं, उनकी दशा देखकर तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो क्या गरीबों की हालत बदतर बनाने के लिए यह सब हो रहा है? आखिर इतनी बड़ी रकम कहां चली जाती है? ऐसे सवालों के जवाब आपको राजस्थान में बिना पूछे मिल सकते हैं। आप सिर्फ दो-तीन दिन राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का चक्कर लगा लें। मगर दो बातों का ध्यान रहे: एक तो बोर्ड के कुछेक अधिकारियों-कर्मचारियों (जो मिलजुलकर लाखों रु० डकार जाने में जितने माहिर हैं, उतने ही शातिर भी हैं) की निगाह से बचिये, दूसरे इस 'जमात' के किसी सदस्य का वास्तविक नाम न लें। अपने मकसद के लिए आप 'क', 'ख' आदि संकेतात्मक नामों से बोर्ड के कर्ताधर्ताओं की चर्चा कर सकते हैं। बेहतर है कि शुरुआत 'क' महाशय की ही चर्चा से की जाये।

लूट की प्रक्रिया: आलीशान वाहन से आने-जानेवाले 'क' महाशय शायद राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के न कोई अधिकारी हैं न कर्मचारी। लेकिन रोब-दाब के लिहाज से ये किसी अधिकारी से कम नहीं हैं। बोर्ड के ही नहीं, राज्य और जिला प्रशासन के लोग भी इन्हें बखूबी जानते हैं। कुछ बरस पहले तक ये जयपुर के एक कारखाने में एक मामूली नौकर हुआ करते थे। पैसा कमाने की ललकवाले 'क' महोदय को एक बार अपने एक रिश्तेदार के स्कूल को अनुदान दिलाने की गरज से बोर्ड के चक्कर लगाने पड़े। इसी क्रम में वे बोर्ड के एक अधिकारी के संपर्क में आये और थोड़ी-सी सूझबूझ व मेल-मिलाप के जरिए लाखों की रकम से खेलने का नुस्खा पा गये। इन्होंने तुरंत एक समाजसेवी संस्था का पंजीयन कराया और बच्चों के कल्याण की एक योजना चलाने के लिए समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में अनुदान के लिए आवेदन कर दिया। अधिकारी ने अपनी दोस्ती निभायी। 'क' महाशय को अनुदान मिल गया। 'क' महाशय ने भी दोस्ती निभायी और तुरंत अनुदान की राशि का एक बड़ा हिस्सा अधिकारी महोदय को नजर कर दिया। श्रीमान 'क' ने अपने मकान पर संस्था का बोर्ड लगा दिया। संस्था का शेष कार्य कागजों पर चलता रहा। निरीक्षण भी हो गया। अधिकारी की मेहरबानी से अच्छी रिपोर्ट आ गयी। दूसरे वर्ष श्रीमान 'क' ने तीन कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर दिये। फिर दूसरे नामों से संस्थाएं खोल लीं। दर्जनों कार्यक्रमों का अनुदान उन्हें मिलने लगा। आज इनके पास अच्छा-खासा मकान तथा ऐशो-आराम की सारी सुविधाएं हैं। ये अपनी नौकरी भी कब की छोड़ चुके हैं।

ऐसे ही श्रीमान 'ख' पहले एक स्कूल मास्टर थे। महत्वाकांक्षा ने जोर मारा, तो उन्होंने खुद का स्कूल खोल लिया। स्कूल जल्दी ही बंद भी हो गया। एक दिन पता चला कि समाज कल्याण बोर्ड शिशु पालना गृह को, संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुदान देता है। कुछ दिन बोर्ड के चक्कर लगा कर अधिकारियों और कर्मचारियों को भेंट-पूजा देकर ये

भी संस्था चलाने लगे। इन्हें भी कई कार्यक्रमों के लिए अनुदान मिलने लगा। इसके बाद इन्होंने अपने पिता के नाम से एक संस्था और खोल ली। आज दोनों संस्थाएं खूब अनुदान उठा रही हैं। वे चल रही हैं बस नाम मात्र को। निरीक्षणकर्ता 'ख' साहब का अपना आदमी होता है। नहीं भी होता, तो निरीक्षण की तारीख की सूचना उनको पहले ही मिल जाती है और वे दो दिन तक संस्था को चलते दिखाने का इंतजाम कर लेते है।

ये तों छोटी. मिसालें है। स्वयं बोर्ड. के सूत्र बताते हैं कि ऐसे अनगिनत मामले हैं। अनुदान दिलाने में बोर्ड में उच्च स्तर तक लेन-देन होता है। शिकायतें आती है, तो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। यह गोरखधंधा साढ़े तीन दशकों से चल रहा है।

३५ साल का चस्का: सन १९५३ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में दुर्गालाल देशमुख ने दिल्ली में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। अगले वर्ष ही राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन हो गया। उस समय समाज के पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए न तो आज जितनी योजनाएं थीं और न उन्हें क्रियान्वित करनेवाले विभागों का अब जैसा जमावड़ा था। सरकार की ओर से थोड़े-बहुत प्रयास होते थे। शेष क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम बोर्ड को सौंपा गया।

समय के साथ राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार पनपता गया। यहां तक कि बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव, परियोजना अधिकारी तथा अन्य लोगों पर भी खुले आम आरोप लगने लगे। अच्छा काम करनेवाली संस्थाओं ने धीरे-धीरे अधिकारियों के रवैये से परेशान होकर बोर्ड से अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया। बीच में तो ऐसा वक्त भी आया कि बोर्ड में सरकारी पैसा आता और अंदर-ही-अंदर गटक लिया जाता। कई पेशेवर संस्थाएं पनप गयीं। वे हर साल हजारों-लाखों रुपए का अनुदान उठाने लगीं। अनुदान का पचास प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी अनुदान का चैक मिलते ही ले लेते। शेष में से ५-१० प्रतिशत राशि संस्था को चलते हुए दिखाने में खर्च की जाती, बाकी संस्थाओं के संचालक चट कर जाते।

एक साल पूर्व तक अध्यक्ष पद पर आसीन रही श्रीमती नगेंद्र बाला के कार्यकाल में तो बोर्ड की छवि बहुत ही बिगड़ गयी। स्वयं उन पर आडिट रिपोर्ट में आरोप लगाये गये थे। कहा जाता है कि उन्होंने कोटा में खुद एक संस्था शुरू करवायी थी, जिसके अध्यक्ष उनके भाई थे। नगेंद्र बाला ने एक काम यह किया कि एक सहायक परियोजना अधिकारी हनुवंत सिंह चौहान को बोर्ड का सचिव बनवा दिया। करीब ३० साल से इसी बोर्ड में काम कर रहे चौहान एक छोटे कर्मचारी से सचिव के पद तक जा पहुंचे। वे आज भी बोर्ड में समाज कल्याण अधिकारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ दर्जनों शिकायतें हुई। महालेखाकार की रिपोर्ट में उनका नाम तीन बार आया, मगर उनको कोई डिगा नहीं सका। आज भी कई पेशेवर संस्थाएं, चौहान को बोर्ड में अपना सबसे बड़ा हितचिंतक मानती हैं। १९६४ से ६६ तक जब वे बोर्ड में कैशियर थे, उन्हें उपकरणों की खरीद में हुई लाखों की गड़बड़ीवाले मामले में दोषी पाया गया। १९६८-६९ की ऑडिट रिपोर्ट में उनके नाम करीब २५ हजार रुपए की वसूली बकाया दिखायी गयी। जानकार लोगों के अनुसार चौहान १९७० से '७२ तक सचिव रहे और उनकी सारी गड़बड़ियां दबा दी गयीं। वे १९८५-८६ में फिर सचिव बना दिये गये। नगेंद्र बाला के कार्यकाल में अनुदान बांटने के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए लिये गये। बोर्ड से जुड़े लोग जानते हैं, उन दिनों नाममात्र को ही कार्यक्रम चलते थे। लेकिन इस दौर ने भ्रष्टाचार का जो चस्का लगा दिया, वह शायद ही कभी छूटे।

फर्जी फर्जअदायगी: बोर्ड की छवि और कामकाज में सुधार की उम्मीद के साथ आज से कोई नौ माह पूर्व श्रीमती सुधा रैना बोर्ड की अध्यक्ष बनायी गयी। लेकिन इस अवधि में वे बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार कर पायी हों, ऐसा लगता नहीं है। पिछले वर्ष भी ज्यादातर उन्हीं संस्थाओं को अनुदान मिल पाया, जो पैसा हड़पने के लिए विख्यात रही हैं। कुछ नयी संस्थाओं ने आवेदन

साक्षात्कार /सुधा रैना

हम कड़ी नजर रख रहे हैं

राजस्थान की चर्चित हस्ती रामजी काक की ३८ वर्षीय पुत्री श्रीमती सुधा रैना युवक कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष पद इन्हें अपनी सक्रियता की सौगात के रूप में मिला। नौ महीने का कार्यकाल बिताने के बाद उनके चेहरे से आत्मविश्वास झलकने लगा है। प्रस्तुत हैं. उनसे बातचीत के प्रमुख अंश :

माया: ***राजस्थान में कितनी संस्थाएं बोर्ड से अनुदान प्राप्त कर रही हैं?***

सुधा रैना: *करीब साढ़े तीन सौ संस्थाएं अभी हम से अनुदान ले रही हैं। पर इस वर्ष मेरा अनुमान है, हम करीब साढ़े पांच सौ संस्थाओं को अनुदान दे सकेंगे। हम चाहते हैं राज्य में इन संस्थाओं का जाल सा बिछ जाये, ताकि हर जगह समाज-सेवा और विकास का कार्य हो सके। इस बार काफी नये पंजीकरण हुए हैं। कई नयी संस्थाएं सामने आयी हैं। जब मैं आयी थी, तब मैंने देखा था कि एक निश्चित ग्रुप में से संस्थाओं का चुनाव होता था। नये लोग काम करना चाहते थे, मगर कठिन कागजी कार्यवाही होने या किन्हीं दूसरे कारणों से वे काम नहीं पाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी जानकारी देनेवाली एक पुस्तिका निकाली। इसीलिए इस बार ज्यादा आवेदन आये हैं। नयी संस्थाओं के साथ एक दिक्कत यह जरूर आती है कि तीन वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत संस्थाओं को हम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन 'अनकवर्ड' क्षेत्रों में काम करने के लिए कोई संस्था आगे आती है, तो उसको बढ़ावा देना हमारा फर्ज है।*

माया: ***क्या आप जानती हैं कि कुछ लोग अलग-अलग नामों से संस्थाएं बनाकर अनुदान हासिल कर रहे हैं, या वे एक से अधिक संस्थाओं की कार्यकारिणी में हैं?***

रैना: *काफी शिकायतें इस तरह की हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को जानती भी हूं जिनके पास पांच-छह संस्थाएं हैं। एक जगह पर ही वे काम कर रही हैं और अलग-अलग स्कीमों के लिए अलग-अलग नामों से वे अनुदान ले रही हैं। इसीलिए हमने एक प्रारूप बनाया है। उसके अनुसार बहुत ही बढ़िया काम करनेवाली संस्था को छोड़कर किसी भी संस्था को दो कार्यक्रम से ज्यादा नहीं देंगे। यह जानकारी होने के बाद कि दो संस्थाएं एक ही आदमी की हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक से ज्यादा कार्यक्रम न दें।*

माया: ***ये भी आरोप लगाये जा रहे हैं कि बहुत सी संस्थाएं सिर्फ कागजों पर हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है?***

रैना: *हां, कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ कागजों पर ही चल रही हैं। इसके लिए हम केवल उन्हें ही दोष नहीं दे सकते। कहीं किसी कारण से कोई संस्था लड़खड़ा जाती है और दुबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है। इस कारण वह केवल कागजों पर ही रह गयी। अगर वह थोड़ा बहुत काम कर रही है और उसका अनुदान हम पूरी तरह बंद कर दें, तो वह वापस कभी खड़ी नहीं हो सकेगी।*

कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ अनुदान लेने के लिए ही कागजों पर चलती हैं। हमें जानकारी मिलती है, तो हम उसी समय उनका अनुदान तो बंद कर ही देते हैं। मैंने काम संभालने के बाद तो इस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। मैं खुद निरीक्षण करने जाती हूं। बोर्ड की सदस्याओं को हमने उनके क्षेत्रों की संस्थाओं की

किया, तो उनके आवेदन में छोटी-मोटी गलतियां निकाल कर उन्हें निरस्त कर दिया गया। कहा जाता है कि छोटी-मोटी संस्थाओं के आवेदन तो सीधे गायब कर दिये जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग दो-दो संस्थाएं बनाकर कई कार्यक्रमों के लिए अनुदान लेने में सफल हो गये। उदाहरण के तौर पर जयपुर में झोटवाड़ा स्थित 'ब्रज बाल मंदिर समिति (कोड नं०-००७७) को शिशु पालना गृह की दो शाखाएं चलाने के लिए अनुदान दिया गया। इस समिति का पता है कलावती भवन, राणाप्रताप नगर, झोटवाड़ा, जयपुर। एक अन्य संस्था को भी दो शाखाएं चलाने के लिए अनुदान दिया गया। इसका नाम है राजस्थान आदर्श विद्यापीठ सोसायटी (कोड नं०-००८२), कलावती भवन, राणा प्रताप नगर, झोटवाड़ा, जयपुर। जाहिर है, इन दोनों संस्थाओं का संबंध एक ही आदमी से है। दोनों के पते भी एक ही हैं। शिशु पालना गृह की एक शाखा चलाने के लिए १४ हजार रुपए अनुदान दिया जाता है। इस तरह इन संस्थाओं को चलानेवाले को ५६ हजार रुपए बतौर अनुदान मिल गये। जानकार सूत्रों के अनुसार उसे बोर्ड के अन्य कार्यक्रम भी मिले हैं, जिनकी अनुदान राशि के रूप में उसे लाखों रुपए मिलते हैं।

जयपुर के सोडाला क्षेत्र में चलनेवाली दो-तीन संस्थाएं भी इसी तरह दर्जनों कार्यक्रम हासिल कर लाखो रुपए का अनुदान प्रति वर्ष उठा रही हैं। इनके कर्ताधर्ता एक दूसरे की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इन्हें अनुदान के रूप में ५ लाख रुपए से अधिक मिले हैं, लेकिन कार्यक्रम के नाम पर लोगों ने इन संस्थाओं को वर्ष में ५ दिन भी चलते नहीं देखा। शिशु पालना गृह (क्रेच) के नाम पर ये संस्थाएं बच्चों की फर्जी सूचियां, फर्जी बिल प्रस्तुत करती रहती हैं। इन संस्थाओं का साल में कम-से-कम एक बार विधिवत निरीक्षण होने का प्रावधान है, पर सूत्रों के अनुसार ऐसी संस्थाएं खुद अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराती हैं तथा उन पर अधिकारियों से दस्तखत करवाकर, उन्हें जमा कर अपना फर्ज पूरा कर देती हैं।

पालना गृह का पेशा : पालना गृह वास्तव में उन गरीब कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए होते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय करीब ३ हजार रुपए होती है। शहरों में भी ऐसे पालना गृहों के लिए अनुदान दिये गये हैं, जबकि वहां इन संस्थाओं को इतनी कम आयवाले परिवार की कामकाजी महिला ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये संस्थाएं नाममात्र को पालने, खिलौने, दूध की बोतल आदि खरीदती हैं, ताकि निरीक्षण के समय उन्हें दिखाया जा सके। ऐसे आड़े समय पर ये स्कूलों से मिल जुलकर कुछ समय के लिए बच्चे भी 'अरेंज' कर लेती हैं।

इसी तरह कुछ संस्थाओं को महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में उन महिलाओं को, जो औपचारिक शिक्षा नहीं पा सकीं, संक्षिप्त पाठ्यक्रम के जरिए प्राइमरी, मिडिल स्कूल तथा मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए तैयार करना होता है। ऐसे पाठ्यक्रम के लिए बोर्ड एक लाख १० हजार रुपए का अनुदान देता है। इसमें महिलाओं को दी जानेवाली छात्रवृत्ति की राशि भी शामिल होती है।

जानकार सूत्र बताते हैं कि ये कार्यक्रम चला रही पेशेवर संस्थाएं साल भर चलती ही नहीं, सिर्फ परीक्षाओं के समय महिलाओं को बुला लेती हैं। वे चाहे पास हों या फेल, उनकी बला से। छात्रवृत्ति की राशि भी संस्थाएं हड़प जाती हैं। मुफ्त किताबें देने का प्रावधान है, पर वे भी नहीं दी जातीं। परीक्षा के समय बुलाकर महिलाओं से छात्रवृत्ति और पुस्तक आवंटन संबंधी कागजात पर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं।

बांझ उत्पादन योजना : बोर्ड का सबसे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम है उत्पादन इकाई का। इसके तहत संस्था को कोई ऐसी उत्पादन इकाई लगाने के लिए ३ से १० लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है, जिसमें महिलाओं को रोजगार मिल सके। इस पैसे से इन संस्थाओं को उत्पादन इकाई के लिए उपकरण और कच्चा माल भी खरीदना होता है। उत्पादन शुरू हो जाने के बाद यह पैसा लौटाना होता है।

लाखों रुपएवाली यह योजना बोर्ड का पैसा हड़पने का सबसे अच्छा जरिया है। ये कार्यक्रम प्रायः अधिकारियों से बहुत ज्यादा मेल-मिलाप

सूचियां दे दी हैं और उनसे कहा है कि वे उनका निरीक्षण करें। संस्था नहीं चलती है, तो हम उसे एक बार चेतावनी देते हैं। उस पर भी वह नहीं सुधरती, तो हम उसका अनुदान काट देते हैं। सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम में ऐसे भी मामले हैं कि संस्थाएं उत्पादक इकाई के लिए अनुदान ले लेती हैं, मगर वह पैसा उसमें लगाती ही नहीं। बोर्ड उनके खिलाफ प्रशासनिक और वित्तीय कार्यवाही तो कर देता है, पर कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाता। क्योंकि बोर्ड के 'लीगल स्टेटस' की समस्या अभी सुलझी नहीं है।

माया : ***आप स्वयं इन संस्थाओं का निरीक्षण करती रही हैं?***

रैना : *मैं तो महीने में पंद्रह दिन इसी काम में लगी रहती हूं। कहीं भी पहुंच जाती हूं। बल्कि काफी नाराजगी और खौफ हो गया है इससे। मैं बोर्ड की सदस्याओं के भी पीछे पड़ी रहती हूं कि वे निरीक्षण करें। अचानक निरीक्षण करने पर जो संस्थाएं काम करती हुई नहीं मिलीं, हमने उनका अनुदान बंद कर दिया। मैं अधिकारियों से भी निरीक्षण करवा रही हूं।*

माया : ***क्या आपने किसी संस्था को अनुदान का दुरुपयोग करते पाया है? पाया है, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?***

रैना : *मैं अभी तक जिन संस्थाओं में गयी हूं, उनमें से ज्यादातर को मैंने काम करते हुए ही पाया है। सदस्याएं जरूर ऐसी संस्थाओं में गयी हैं जहां पर कोई काम होता हुआ नहीं पाया गया है। हमने ऐसी संस्थाओं का अनुदान बंद कर उन्हें नोटिस दे दिये हैं। उनका अगर कोई दूसरा कार्यक्रम भी चलता है, तो हमने उन्हें चेतावनी दे दी है कि अगर आपका यह कार्यक्रम नहीं सुधरेगा, तो हम दूसरे कार्यक्रम का अनुदान भी बंद कर देंगे। उन्हें यह भी कहा जाता है कि या तो आप पैसा वापस जमा कराइये, नहीं तो आपको अगले वर्ष कार्यक्रम नहीं दिया जायेगा।*

माया : ***संस्थाओं को कार्यक्रम चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता है, क्या वह कार्य को देखते हुए पर्याप्त होता है?***

रैना : *हाल ही संक्षिप्त पाठ्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पैसा बढ़ा दिया गया है। वह तो काफी अच्छा अनुदान हमें दे रहे हैं। हां, अवकाश शिविर कार्यक्रम का पैसा पर्याप्त नहीं है। उसे हमें बढ़ाना होगा। शिशु पालना गृह का अनुदान ठीक ही है।*

माया : ***अध्यक्ष की हैसियत से बोर्ड का काम अधिक सार्थक बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं?***

रैना : *जो संस्थाएं गलत अनुदान उठा रही थी, मैंने उन पर कड़ी कार्यवाही करनी शुरू की। साथ ही जो नये लोग कार्य करना चाहते थे, उनको प्रोत्साहन दिया। संस्थाएं बनवायीं और अपने साथ जोड़ा। हमने निश्चय कर लिया है कि जैसे ही अनुदान का पैसा हमारे पास आयेगा, उसे रोकेंगे नहीं। पहले यह शिकायत रहती थी कि आवेदन भेजने के बाद पता नहीं चल पाता था कि उसका क्या हुआ। अब हम जवाब भेजते हैं कि आवेदन विचाराधीन है, या निरस्त हुआ है, तो किन कारणों से। जिलों में काम करनेवाले स्वयंसेवी संगठनों से हमने बोर्ड की सदस्याओं के माध्यम से सूचनाएं लेनी शुरू की है कि उन क्षेत्रों की क्या जरूरत है और राज्य का समाज कल्याण विभाग वहां क्या कर सकता है? इसके लिए हमने कई संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित कीं। हमने संस्थाओं के सामने आनेवाली कठिनाइयों को जानने के लिए एक अलग कार्यशाला आयोजित की। इस समय मैं कह सकती हूं कि स्वयंसेवी संस्थाओं का बोर्ड से बहुत अच्छा संबंध चल रहा है। बोर्ड को जिस तरह के सेतु का काम करना चाहिए, वह हम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं।*

माया : ***बोर्ड के कुछ अधिकारियों के खिलाफ समय-समय पर आरोप लगते रहे हैं। क्या उनकी जांच और कार्यवाही हुई?***

रैना : *जिनकी शिकायतें हुई हैं, उनकी जांच करवायी गयी है। अभी मुझे काम संभाले ८ महीने ही हुए हैं। जांच में मैंने जिनको दोषी पाया है, उनके कागज केंद्रीय बोर्ड को कार्यवाही के लिए भेज दिये गये हैं।*

—मु०जै०

रखनेवाली संस्थाओं को ही दिये जाते रहे हैं। किंतु मुश्किल से ही ऐसी कोई संस्था मिलेगी, जिसने अनुदान की राशि उठाने के बाद उत्पादन का काम शुरू किया हो। इस कार्यक्रम में ज्यादातर इकाइयों को रुग्ण घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उत्पादन शुरू न हो पाने की स्थिति में पैसा वापस वसूलने का प्रावधान है, मगर एक बार गया हुआ पैसा मुश्किल से ही वसूल हो पाता है। अगर होता भी है, तो इतने वर्ष बाद कि संस्था के कर्ताधर्ता उस पैसे को तब तक दुगना-तिगुना कर चुके होते हैं। आज ऐसी कई संस्थाओं में बोर्ड के लाखों रुपए लटके हुए हैं।

गरीब विधवाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के नाम पर समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड डेयरी कार्यक्रम भी संस्थाओं के माध्यम से चलाता है। जानकार सूत्रों के अनुसार बीसियों गाय-भैंसों की खरीद दिखानेवाली संस्थाओं में से ज्यादातर ने एक बकरी तक नहीं खरीदी है। लेकिन फाइलों में बाकायदा डेयरी चलती बतायी जाती है। पशुओं के फर्जी बीमे तक करवा दिये जाते हैं।

गरीब बच्चों को दूसरे शहरों का जीवन तथा वहां का माहौल दिखाने के लिए बोर्ड संस्थाओं के माध्यम से बाल-अवकाश शिविर आयोज़ित करता है। तीस से पचास बच्चों के शिविर के लिए करीब साढ़े ६ हजार से १० हजार रुपए तक का अनुदान मिलता है। चूंकि ये शिविर बहुत छोटी अवधि के होते हैं, इसलिए इनके जरिए पैसा हड़पना बहुत आसान होता है। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए करीब ढाई लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है। यहां भी वही स्थिति है। कुछ संस्थाएं प्रशिक्षण दे भी रही हैं, मगर नाममात्र के लिए। न वे पर्याप्त सामान खरीदती हैं, न पर्याप्त संख्या में महिलाएं सीखने आती हैं। हर चीज को बढ़ा-चढ़ा कर बता दिया जाता है। इनके अलावा महिलाओं का जन सहयोग प्रशिक्षण शिविर, पोषाहार, बालबाड़ी, आदि कई कार्यक्रम चलाने के लिए बोर्ड संस्थाओं को अनुदान देता है। मगर प्रायः हर कार्यक्रम में ये कथित समाजसेवी संस्थाएं जम कर पैसा लूटती हैं।

कार्रवाई कौन करे? :समाज कल्याण बोर्ड को वर्ष १९८८-८९ में अनुदान देने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड से करीब ९०लाख रुपए मिले। जल्दी ही यह राशि एक करोड़ प्रति वर्ष से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। इस तरह अब तक बोर्ड करोड़ों रुपए अनुदान के रूप में संस्थाओं को दे चुका है। सब कहते हैं कि इस अनुदान का ९० प्रतिशत पैसा संस्थाओं के कर्ताधर्ताओं और बोर्ड के अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। फिर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब किसी संस्था के खिलाफ कार्रवाही करना जरूरी हो जाता है, तो वह सिर्फ प्रशासनिक या वित्तीय स्तर तक होती है। राज्य बोर्ड संस्था के खिलाफ आरोपपत्र तैयार करके केंद्रीय बोर्ड को भेज देता है, जहां से संस्था को अगली बार अनुदान नहीं मिलता। पर संस्था के पदाधिकारी तुरंत दूसरे नाम से संस्था बना लेते हैं और फिर अनुदान के लिए आवेदन कर देते हैं। यों गोरखधधा चलता रहता है, मगर कानूनी कार्यवाही कभी नहीं होती। खुद बोर्ड अपना 'लीगल स्टेटस' अभी तक हासिल नहीं कर पाया है।

श्रीमती सुधा रैना ने अध्यक्ष बनने के बाद शुरू में बड़ा जोश दिखाया था। बोर्ड की सदस्याओं में कुछ ऐसी महिला कार्यकर्ता पहली बार शामिल की गयीं जिन्होंने वास्तव में सामाजिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठा पायी थी। मगर बोर्ड के पुराने अधिकारियों के आगे रैना और उनकी महिला सदस्यों की नहीं चल पायी। बोर्ड की बैठकों में प्रायः उन्हें मूक दर्शक बने बैठे देखा गया। कई संस्थाओं का निरीक्षण करके उनका अनुदान बंद करवाया गया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें अनुदान वापस पाने के रास्ते बता दिये।

श्रीमती रैना ने भी अब अपने अधिकारियों से सिर खपाना कम कर दिया है। बोर्ड के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी रखनेवाला व्यक्ति जानता है कि समाज कल्याण के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपए कहां जा रहे हैं। नहीं जानते, तो सिर्फ वे गरीब लोग जिनके कल्याण के नाम पर यह लूट मची है। जिन स्थानों पर संस्थाएं चलती हैं, उनके आसपास रहनेवाले गरीब लोग यह भी नहीं जानते कि उनके पडोस में ऐसा कार्यक्रम चलाने का नाटक हो रहा है जिन पर वास्तव में उन जैसे लोगों का हक है।

—**भुवनेश जैन**

You have read this issue of
PROBE INDIA

The palette was full of indepth news stories that are current—special reports, investigations, focus, sports, crime, films, colour features, and to top it all, an interesting cover story.
And the next issue will have fresh, equally interesting stories—revealing, provocative and satisfying.

Could you afford to miss the next number? You can ensure your next 12 issues at your office or home without ever having to miss it at our annual subscription offer of Rs. 50/- only. You save over 25% on news-stand price.

PROBE INDIA
Tells more than told so far

A Mitra Prakashan Publication

Please send next 12 issues of PROBE INDIA
at **Rs. 50** only, as against **Rs. 72.00** (news-stand price)

Name Mr./Mrs./Miss ....
(in block letters)
Address ....
....
.... Pin ☐☐☐☐☐☐

I am enclosing ☐ Postal Order ☐ Bank Draft for Rs 50.00 in favour of Mitra Prakashan Pvt. Ltd., Allahabad.

Date .... Signature ....

Please fill in and send to Circulation Manager, Mitra Prakashan Pvt. Ltd., 281, Muthiganj, Allahabad-211003 together with remittance.
Cheques not accepted.

आँखें खोल कर खरीदें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ ही खरीदें

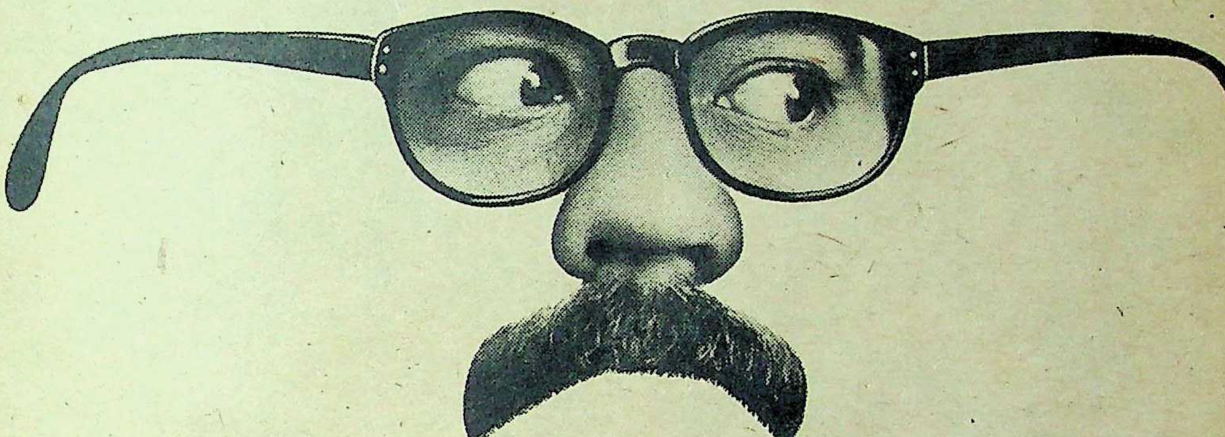

जरा सोचिए—आप डीलर के पास जाएं और सिर्फ "एक कूलर" की मांग करें बिना देखे कि उस कूलर में कौन सा कूलर पंखा व पम्प लगा है।

यह न जानते हुए कि शायद आप पाएं एक ऐसा कूलर जिसमें घटिया व पुरानी तकनीक से बना कूलर पंखा व पम्प लगा हो। सिवाय इसके कि आप आँखें खोलकर किसी एक नाम की मांग करें।

सिर्फ पोलर ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि पोलर कूलर पंखा और पम्प की मोटर पर चढ़ी बेक्टाल-2 की दोहरी परतें इसे जलने के खतरे से सुरक्षित रखती हैं और डाईनामिकली बेलेन्स् ब्लेड अधिक हवा देते हैं।

इसलिए आप जब भी कूलर खरीदें आँखें बंद करके न खरीदें। **विचार करें** और पोलर ही खरीदें क्योंकि सिर्फ पोलर ही 100% भरोसेमंद हैं।

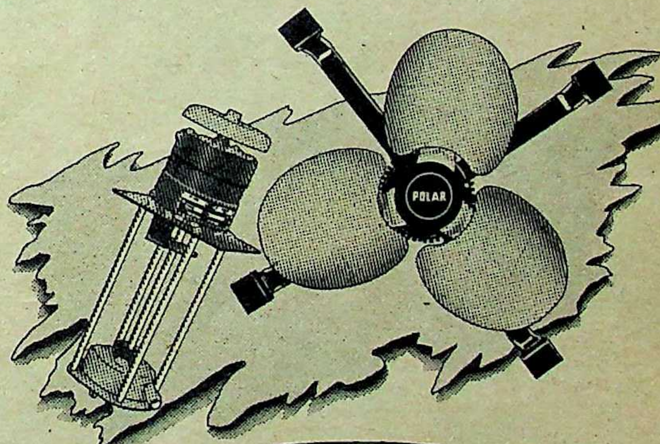

पोलर

कूलर पंखा & पम्प

सिर्फ सर्वश्रेष्ठ खरीदें - पोलर ही खरीदें

Pavitra/3291/2

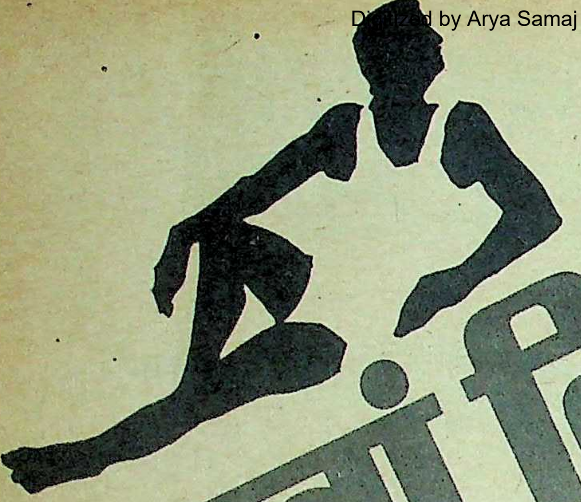

जवां दिलों की पहली पसंद

RUPA®

मुलायम व फाइन सूती धागे से बने। रेशम सी कोमलता का अहसास। उत्तम फिनिश और मजबूत सिलाई। हर एक के लिए सही साइज। फिटिंग पूर्णतः आरामदायक। इम्पोर्टेड रबर से बने इलास्टिक। मनपसंद विभिन्न रंगों में लीजिए।

गंजी, जाघिया, पेण्टीज़

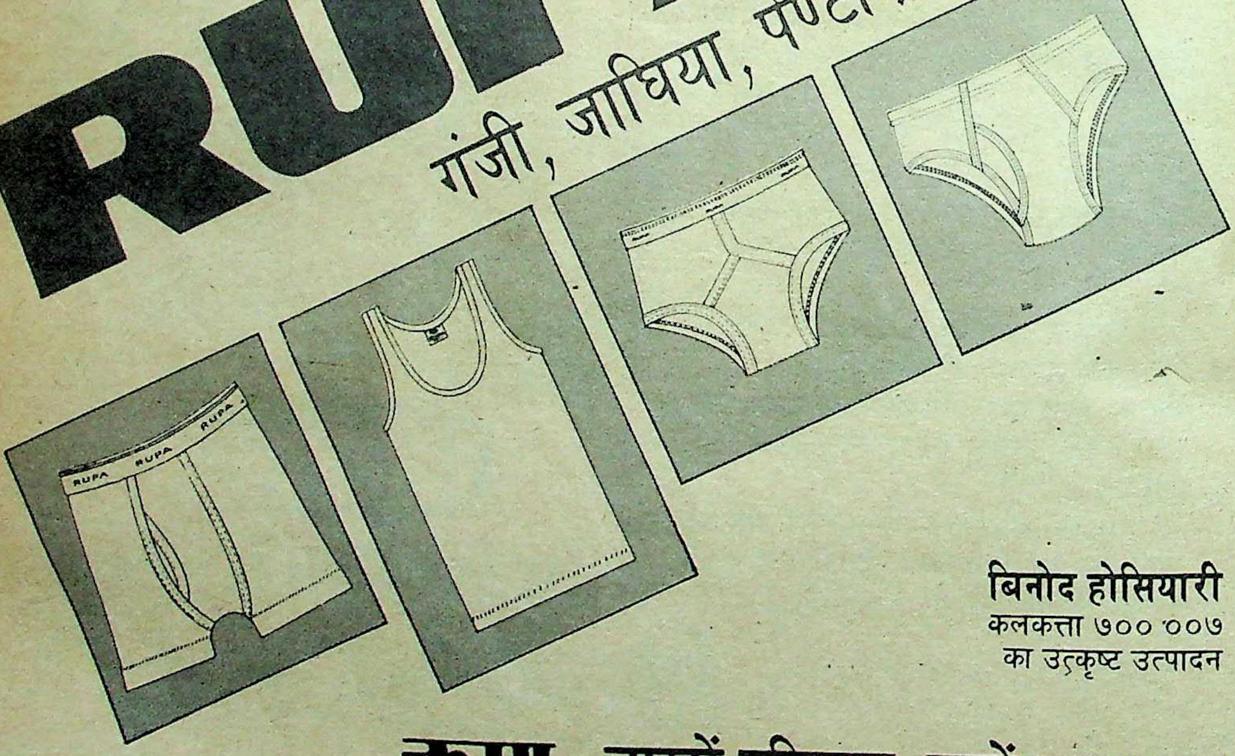

बिनोद होसियारी
कलकत्ता ७०० ००७
का उत्कृष्ट उत्पादन

रूपा – लाखों परिवार, पहनें बार बार

DPS/BH-881

दो नेता अधर में

बिरादरी का मारा: रामनरेश यादव

माया मिली न राम: राजमंगल पाण्डेय

दिल में बड़े-बड़े अरमान लेकर राजमंगल पाण्डेय ने कांग्रेस-इ से जनता दल और रामनरेश यादव ने जनतादल से कांग्रेस-इ में पाला बदला था। लेकिन जनता पार्टी के शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे रामनरेश यादव को पाला बदलने के बाद कांग्रेस-इ में भूतपूर्व मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, तो राजमंगल पाण्डेय भी अधर में ही हैं।

रामनरेश यादव को कोई महत्वपूर्ण पद दिये जाने में उनके सजातीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम सिंह यादव सहित उन्हीं के जिले के चंद्रजीत यादव और बनारस से चुने गये केंद्रीय राज्यमंत्री श्यामलाल यादव का अंदरूनी विरोध आड़े आ रहा है। यादव मतों के नाम पर पार्टी में अपनी पैठ जमानेवाले इन तीनों नेताओं को अपने वर्चस्व में इंका के नये-नवेले रामनरेश यादव की भागीदारी रास नहीं आ रही है। दूसरी ओर, इंका के वे कार्यकर्ता और नेता जो कई वर्षों से कोई पद प्राप्त करने की लालसा में हैं, खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि वे यह कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पार्टी में पहली बार आये रामनरेश यादव को कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाये।

ठीक ऐसी ही स्थिति इंका से विमुख होकर जनता दल में शरीक हुए राजमंगल पाण्डेय की है। पाण्डेय ने आपातकाल के दौरान वर्ष १९७६ में पहली बार हेमवतीनंदन बहुगुणा के साथ कांग्रेस छोड़ी थी। तब वे जगजीवन राम की लोकतांत्रिक कांग्रेस में शामिल हुए थे। १९८३ में विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रयासों से ही वे कांग्रेस में वापस लौटे थे। अब पुनः उन्ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हें जनता दल में बुला लिया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार तथा ब्राह्मण लाबी के सशक्त नेताओं में गिने जानेवाले राजमंगल पाण्डेय एक अहमियतदार नेता हैं। बावजूद इसके, पक्ष-विपक्ष में पदों को लेकर चली आ रही उठा-पटक की परम्परा मे उन्हें तरजीह नहीं मिली। प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य रह चुके पाण्डेय वर्ष १९८३ में कई वायदों के साथ इंका में वापस लाये गये थे। प्रदेश की राजनीति में कई बार उनका नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उभरकर चर्चा में आया था। यही वजह थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी वे इंका में बने रहे।

आखिरकार, इंका छोड़ने के पीछे पाण्डेय की कई कुंठाएं हैं। पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद न मिलना एक कारण तो था ही, हताश वे तब हुए जब उनके ही जिले देवरिया में हाईकमान ने उनकी उपेक्षा की। इंका में रहने तक वे इसी जिले के सांसद थे। स्थानीय निकाय के चुनाव में हाईकमान ने उनकी जगह जिले के दूसरे इंका सांसद रामनगीना मिश्र को तरजीह दी। प्रदेश स्तर पर अपनी राजनीतिक साख रखनेवाले पाण्डेय का अपने ही जिले में मात खाना इंका के प्रति उनकी विमुखता का कारण था। इंका में अपने होने का अहसास कराने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अनेक खत लिखकर उन्हें पार्टी के मामलों में कई मशविरे दे डाले थे।

वीपी सिंह उन्हें कांग्रेस में वापस लाये थे, लेकिन उन्हें किसी ऊंची कुरसी पर बिठा न सके थे। यही वजह थी कि जब वीपी सिंह ने इंका छोड़ी, तो पाण्डेय उनके बगलगीर नहीं हुए। दूसरी ओर, वीपी सिंह उनकी कुंठा को परखकर उनसे जनता दल में आने के लिए सम्पर्क साधे हुए थे। आखिरकार, इंका में हताशा की राजनीतिक जिन्दगी बसर कर रहे राजमंगल पाण्डेय की मजबूरन जनता दल में कदमबोशी हुई। पाण्डेय को उम्मीद थी कि जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते वीपी सिंह उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद अदा फरमायेंगे। लेकिन उनकी इस उम्मीद को घटकवाद निगल गया। उन्हें जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव बनाये जाने की चर्चाएं भी चलीं, लेकिन ये सारी चर्चाएं दल में चल रहे यादवी संघर्ष में हलाक हो गयीं। यही कारण है कि इस नयी छलांग के बाद भी राजमंगल पाण्डेय हताशा के ही दौर से गुजर रहे हैं। पाण्डेय ने पार्टी के साथ-साथ संसद की सदस्यता भी छोड़कर वर्तमान राजनीति में जिस ईमानदारी का परिचय दिया था, उसका कोई प्रतिफल फिलहाल उन्हें जनता दल में नहीं मिला।

बहरहाल, रामनरेश यादव और राजमंगल पाण्डेय जिस उम्मीद से नये खेमे में प्रविष्ट हुए, वह दिनोदिन क्षीण होती जा रही है। अब हालत यह है कि दोनों नेता अधर में हैं। वे वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और अब एक बार फिर पाला बदलना उनके वश की बात भी नहीं रह गयी है।

—सुरेश द्विवेदी

अरुण नेहरू व यशपाल कपूर आमने-सामने

कहावत है कि 'घूरे के दिन भी बदलते हैं,' फिर यशपाल कपूर तो राजनेता हैं, वह भी पुराने और मंजे हुए। भांजे आरके धवन की वापसी के साथ ही मामा यशपाल कपूर के दिन भी बहुरने लगे हैं। कपूर साहब एक जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी के दरबार के दमकते रत्न थे और श्रीमती गांधी के प्रमुख संकटमोचक दूतों में यशपाल कपूर का भी नाम लिया जाता था। शायद इसी कारण आम चुनाव के पूर्व राजीव गांधी को उनका महत्व समझ में आने लगा है। यही वजह है कि उन्हें रायबरेली में इंका के हितों की देखभाल करने का दायित्व सौंप दिया गया है।

राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र रायबरेली पर राजीव गांधी स्वयं कड़ी नजर रख रहे हैं। अमेठी के साथ ही वे रायबरेली को भी सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। रायबरेली से अरुण नेहरू का पत्ता साफ करने के लिए पहले वीर बहादुर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी जानेवाली थी। चर्चा है कि यह खबर फैलते ही सिंचाई विभाग के कई ठेकेदार रायबरेली से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गये। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री की विशेष खुफिया टीम ने इसकी गोपनीय रिपोर्ट उन तक पहुंचा दी। फलस्वरूप, राजीव गांधी ने विचार बदल दिया। इसी के बाद रायबरेली की २० सूत्रीय कार्यक्रम की प्रभारी तथा प्रदेश की शिक्षामंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी को बदल कर हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती दीपा कौल को जिले का भार सौंप दिया गया था।

रायबरेली का इंचार्ज बनते ही श्रीमती दीपा कौल के कार्य करने का ढंग ही बदल गया। ऐसा प्रतीत

होने लगा, मानो रायबरेली संसदीय क्षेत्र से आम चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार वे ही रहेंगी। २२ से २४ नवम्बर, १९८८ तक जब राजीव गांधी ने अपने चुनाव-क्षेत्र का तीन दिवसीय दौरा किया, तो वे रायबरेली भी गये। रायबरेली के राजकीय इंटर कालेज के मैदान में प्रधानमंत्री ने जिस जनसभा को सम्बोधित किया था, उसमें मंच पर दीपा कौल को काफी प्रमुखता दी गयी। इसी के साथ चर्चा चल निकली कि दीपा कौल को ही रायबरेली से अरुण नेहरू के मुकाबले लाया जायेगा। श्रीमती दीपा कौल नेहरू परिवार से सम्बन्धित हैं और वे सांसद शीला कौल की पुत्री हैं। उनका बढ़ता रुतबा देख रायबरेली के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने यह खबर प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी कि दीपा कौल के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर से जिले में विद्रोह पनप सकता है। श्रीमती गांधी की इस सीट से या तो स्वयं वे लड़ें अथवा श्रीमती सोनिया गांधी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लें।

साख में सेंध: अरुण नेहरू

बदले की घात: यशपाल कपूर

दरअसल, रायबरेली के कांग्रेसियों को यह भय सता रहा है कि यदि यशपाल कपूर रायबरेली में पुनः जम गये, तो उनका क्या होगा?

फिर क्या था? दीपा कौल से रायबरेली का कार्य-भार ले लिया गया। इसी दौरान अरुण नेहरू ने भी रायबरेली पहुंचकर अपना जनसम्पर्क बढ़ाना शुरू किया। इसे प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया। संकट का भास होते ही उन्हें अपनी मां के संकटमोचक यशपाल कपूर की याद आ ही गयी। यशपाल कपूर से दिल्ली दरबार ने सेवाएं मांगीं। वे तो तैयार ही बैठे थे। ऊपर का इशारा पाते ही यशपाल कपूर ने पहले अपने विशेष दूतों को रायबरेली भेजकर पुराने सम्पर्कियों को संदेशा भिजवाया। फिर ११ अप्रैल, १९८९ को वे खुद रायबरेली पहुंच गये। कपूर फीरोज गांधी डिग्री कालेज के अध्यक्ष भी हैं। प्रचारित यही किया गया कि यशपाल कपूर डिग्री कालेज का मुआयना करने ही रायबरेली आये थे। पर वास्तविकता यह थी कि कपूर ११ से १३ अप्रैल, १९८९ तक रायबरेली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं से गांव-गांव जाकर सम्पर्क करते रहे और पुराने सम्बन्धों की याद ताजा कराते रहे। ठीक एक वर्ष पूर्व १० व ११ अप्रैल, १९८८ को भी यशपाल कपूर ने सन् १९७७ के बाद पहली बार राजनीतिक दृष्टि से क्षेत्र से सम्पर्क साधा था। उस समय भी रायबरेली की राजनीति में सरगर्मी आ गयी थी।

वास्तव में आज भी रायबरेली में ग्रशपाल कपूर का गांव-स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं सें अच्छा सम्पर्क है। इसी कारण अरुण नेहरू के खेमे मे खलबली मची हुई है। अरुण नेहरू ने किस प्रकार से यशपाल कपूर को काटा था, यह तथ्य राजनीति में जरा-सी दिलचस्पी लेनेवाला भी भले प्रकार जानता है। अब वही यशपाल कपूर अरुण नेहरू से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए उनके चुनाव क्षेत्र में सेंध मार रहे हैं।

कांग्रेस-इ में मौजूद अरुण नेहरू समर्थकों ने यशपाल कपूर को भारी पड़ते देख यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यशपाल कपूर रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पर यशपाल कपूर कोई नये खिलाड़ी तो हैं नहीं जो रायबरेली का मूल्यांकन राजीव गांधी के इच्छानुसार न कर स्वयं के मनमाफिक करें। खुद को विवाद से बचाने के लिए उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के नाम की चर्चा चलवा दी। दरअसल, रायबरेली के कांग्रेसियों को यह भय सता रहा है कि यदि यशपाल कपूर रायबरेली में पुनः जम गये, तो उनका क्या होगा?

यशपाल कपूर ने जब से रायबरेली का चार्ज लिया है, सोनिया गांधी को वहां से चुनाव लड़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यह सब कपूर की दिमागी उपज ही है। अब प्रधानमंत्री को यह भी समझाया जा रहा है कि विरोधी लोग उन पर लगाये जानेवाले आरोपों से गाह-बगाह सोनिया गांधी का नाम भी उछालते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी या सांसद न होने के कारण सोनिया अपना बचाव नहीं कर पाती हैं। चूंकि, रायबरेली श्रीमती इंदिरा गांधी और फीरोज गांधी का प्रिय कार्यक्षेत्र रहा है, इस कारण यदि उनकी बहू (सोनिया गांधी) इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, तो उनके समक्ष कोई टिक नहीं सकेगा। सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अमेठी की तरह वह सीट भी कांग्रेस के लिए सुरक्षित हो जायेगी।

संभावना है कि कपूर, राजीव गांधी को समझा भी ले जायें, इसी चाल से वे अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी अरुण नेहरू सें बदला भी चुका सकते हैं।

—निशीथ जोशी

वीपी-बब्बर में खटपट?

कांग्रेसपरस्त 'कलियुगी राम' (अरुण गोविल) के आडंबर को बेअसर करनेवाले अभिनेता राज बब्बर क्या वीपी सिंह के लिए बेमानी हो गये हैं? क्या चुनाव के दृष्टिकोण से वे उपयोगी नहीं रहे? या वीपी सिंह से बब्बर की खटक गयी है? क्या भावी प्रधानमंत्री (वीपी, जैसा कि रैली में ऐलान किया गया) के राजनीतिक अभियान में राज बब्बर की जगह अनूप जलोटा लेंगे? बंबई के विशाल मैदान शिवाजी पार्क में ६ मई की विपक्षी रैली का जायजा लेनेवाले प्रायः सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राज बब्बर, विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह (राजा साहब) के 'मानस शिष्य' माने जाते रहे हैं। दोनों की अंतरंगता के कारण ही वीपी सिंह ने इंका छोड़ने के बाद सबसे अधिक बंबई की यात्रायें कीं, हर यात्रा पर 'बब्बर' चाहे जहां भी होते, मौके पर पहुंचकर अपने गुरु की शानदार अगवानी करते रहे। लेकिन ६ मई की राष्ट्रीय रैली के मौके पर वे कहीं भी दिखायी नहीं पड़े, और सवाल उठने का यही सबब है।

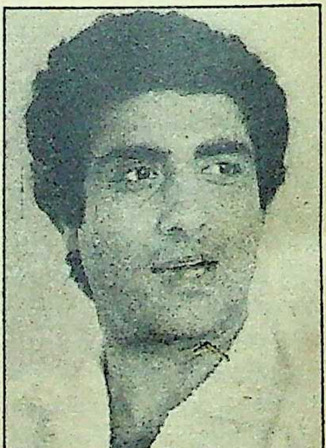

कहां थे?: राज बब्बर

रैली में जहां राजा साहब की बगल में राज बब्बर का गंभीर चेहरा

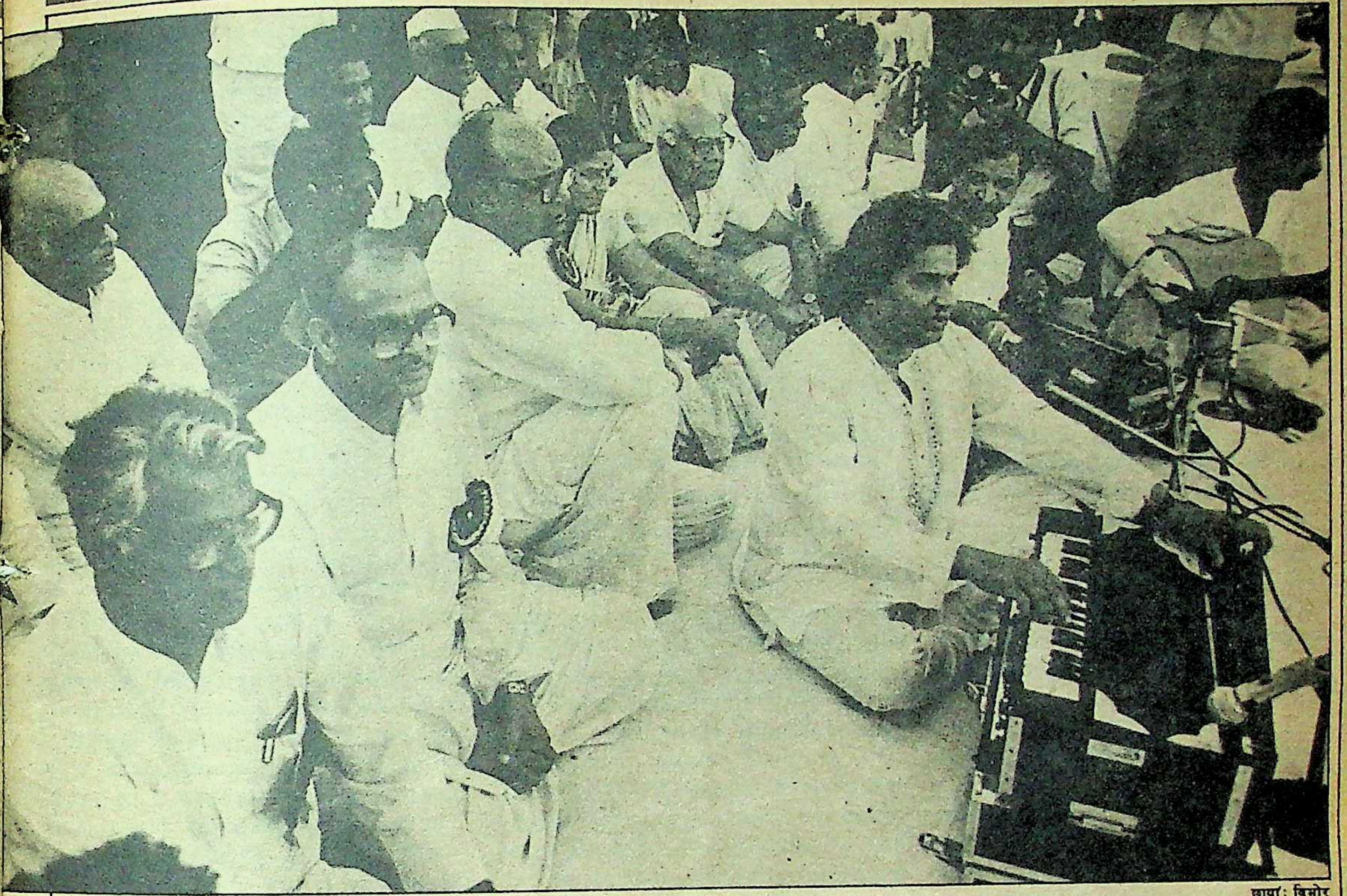

छाया: विनोद

बब्बर की जगह जलोटा: बंबई में विपक्ष की राष्ट्रीय रैली

दिखना चाहिए था, वहां राजा साहब के ठीक आगे हारमोनियम के साथ बैठे प्रख्यात गजल-भजन गायक अनूप जलोटा दिखलायी पड़े। निश्चय ही जलोटा ने अपने साजिंदों के साथ गजल, भजन और गीत रैली में मौजूद भीड़ को सुनाकर नेताओं से खूब वाहवाहियां और तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। उनका गायन इतना आकर्षक और सुखद था कि शिवाजी पार्क के चारों ओर बनी सड़कों पर से गुजरनेवाले लोग भी, बार-बार कैसेटों, रेंकार्डों तथा टीवी पर सुनी जानेवाली अनूप की गजलों व भजनों को सुनने के लिए ठहर गये।

भाजपा ने अपने उदयपुर सम्मेलन में जिस तरह भावी प्रधानमंत्री के रूप में अटलबिहारी वाजपेयी के नाम की घोषणा की थी, उसी तरह जनता दल के नेताओं ने भी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम की घोषणा भी भावी प्रधानमंत्री के रूप में इस रैली में कर दी।

तो क्या आगामी आम चुनाव में जनता दल के चुनाव जीतने के बाद भावी प्रधानमंत्री के नाम को लेकर चल रहे विवादों और अटकलबाजियों पर पूर्ण विराम लग गया? जिस तरह से पहले की घोषणाओं एवं वायदों के बावजूद प्रतिपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर एवं रामकृष्ण हेगड़े सहित कई राष्ट्रीय नेता इस राष्ट्रीय रैली में नदारद दिखलायी पड़े, उससे अटकलों का बाजार नये सिरे से गरमा गया है। इस बारे में उठाये गये सवालों को राजा साहब बड़ी चतुराई से टाल गये और सिर्फ प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री शंकर राव चह्वाण तथा लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ को ही अपने हमले का निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहीं भी शरद पवार पर जो शंकर राव चह्वाण के 'दुश्मन नंबर एक' हैं, अपना निशाना नहीं साधा।

अनूप जलोटा को, राज बब्बर की अनुपस्थिति में, दर्शकों के मनोरंजन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था या वे खुद आये थे? इसका जवाब अनूप जलोटा बड़ी सफाई से टाल जाते हैं, जबकि रैली के अध्यक्ष डा० दत्ता सामंत का कहना है, "अनूप ने रैली में जो ये गीत गाये वे उन्होंने विशेष रूप से सिंह साहब (वीपी सिंह) के लिए तैयार किये थे। इनके मन में राजा साहब के लिए बड़ी श्रद्धा है और इस आयोजन के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया।" इस पर एक पर्यवेक्षक की टिप्पणी है, "आम चुनाव में जब 'कलियुगी राम' (अरुण गोविल) कांग्रेस पार्टी के समर्थन में प्रवचन करेंगे तब 'रामायण' (सीरियल) के गायक अनूप जलोटा जनता दल के पक्ष में रामभजन सुनाकर मतदाताओं की आत्मशुद्धि करेंगे।

इस रैली का रूप रंगारंग कार्यक्रम जैसा था। भीड़ भी मजे की थी, पर भीड़ के बारे में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की टिप्पणी थी, "इससे ज्यादा भीड़ तो हमारी मामूली रैलियों में इकट्ठी होती है।..."

—बंबई ब्यूरो

पहले की घोषणाओं एवं वायदों के बावजूद प्रतिपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, चंद्रशेखर एवं रामकृष्ण हेगड़े सहित कई राष्ट्रीय नेता इस राष्ट्रीय रैली में नदारद दिखलायी पड़े, उससे अटकलों का बाजार नये सिरे से गरमा गया है।

अध्यक्षों में द्वंद्वयुद्ध

बलराम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव

आगामी आमचुनाव की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है और न ही यह तय हुआ है कि कांग्रेस-इ का कौन-सा महारथी विपक्ष के किस महारथी से लोहा लेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस-इ अध्यक्ष बलराम सिंह यादव और जनता दल अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बीच चुनावी जोड़तोड़ का द्वंद्वयुद्ध शुरू हो गया है। यह संयोग ही है कि दोनों अध्यक्ष इटावा जिले के ही हैं और कुशल राजनेता की तरह वे एक दूसरे के खिलाफ जैसी चालें चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अपनी-अपनी पार्टियों के दोनों सेनापति आमचुनाव के निर्णायक युद्ध के पहले ही एक दूसरे को पछाड़कर आमचुनाव की जीत-हार का फैसला कर लेना चाहते हैं।

रामनरेश यादव के कांग्रेस-इ में शामिल हो जाने के बाद तो बलराम सिंह यादव के लिए यह और भी जरूरी हो गया है कि वे मुलायम सिंह यादव को उन्हीं के गढ़ में पछाड़कर यह साबित करें कि कांग्रेस-इ की चुनावी नैया को पार लगाने की काबिलीयत उनके पास है। दूसरी ओर, अपने दमखम पर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष पद पर आसीन होनेवाले मुलायम सिंह यादव के लिए भी यह सुनहरा मौका है कि अपने ही गढ़ में वे आम चुनाव के पहले ही बलराम सिंह के हौंसले पस्त कर दें।

ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है मुलायम सिंह यादव इटावा जिले की राजनीति में बलराम सिंह यादव पर हावी रहे हैं। गत वर्ष हुए स्थानीय निकायों—नगरपालिका, जिला परिषद और सहकारी बैंकों—के चुनाव में मुलायम सिंह के लोग मुख्यतः जीते थे। यहां तक कि बलराम सिंह यादव अपने ही ब्लाक में लोकदल प्रत्याशी को विजय का सेहरा बांधते हुए देखने के लिए मजबूर कर दिये गये थे। वैसे भी इटावा की सात विधानसभाई सीटों में पांच पर विपक्ष (चार-लोकदल, अब जनतादल, एक-भाजपा) का कब्जा है। स्वयं बलराम सिंह यादव के अपने भरथना क्षेत्र की विधानसभा सीट लोकदल के कब्जे में है। लेकिन इधर पांच-छह महीनों में बलराम सिंह यादव ने भीतर-ही-भीतर मुलायम सिंह के खास-खास सिपहसालारों को अपनी ओर फोड़कर इटावा का राजनीतिक माहौल बदलने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए उन्होंने बड़ी सूझबूझ से अपनी चालें चली हैं।

बलराम के प्रहार: यह बलराम सिंह की जोड़तोड़ का ही करिश्मा है कि कभी मुलायम सिंह का दाहिना हाथ रहे दर्शन सिंह यादव आज उनके साथ नहीं हैं। समाजसेवी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ दर्शन सिंह यादव ने ही मुलायम सिंह से किनारा नहीं किया, बल्कि करहल के ब्लाक प्रमुख सुभाष यादव ने भी उनका साथ छोड़कर उन्हें गहरा झटका दिया है। सुभाष यादव, मैनपुरी, इटावा और एटा जिलों में विपक्ष के एक मजबूत स्तंभ रहे स्व० नत्थू सिंह यादव के पुत्र हैं। १९५७, १९७४ और १९७७ में वे करहल (मैनपुरी) से विधायक चुने गये थे। १९६२ में वे जसवंतनगर (इटावा) से विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन १९६७ में उन्होंने इस सीट पर अपने प्रियपात्र मुलायम सिंह यादव को लड़वाया और विजयी बनवाया था और वे मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे। आज उनके इन्हीं गुरु के पुत्र सुभाष यादव, दर्शन सिंह यादव के साथ कांग्रेसी खेमे में पहुंच चुके हैं। इससे मुलायम सिंह की छवि ही धूमिल नहीं हुई, बल्कि उनकी चुनावी ताकत को भी भारी चोट पहुंची है।

इन दोनों के साथ-साथ बरौली कलां के ग्रामप्रधान व क्षेत्र के युवा लोकदल नेता मानिक चंद्र अग्रवाल ने भी मुलायम सिंह का साथ छोड़ दिया है। तीनों ने ठीक उस दिन (१८ मार्च) प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर अपने साथियों सहित जनता दल छोड़ने की घोषणा की, जिसके अगले दिन (१९ मार्च) मुलायम सिंह ने करहल में जनता दल की एक विशाल रैली आयोजित की थी, जिसे हेमवती नंदन बहुगुणा की अकस्मात मृत्यु के कारण स्थगित करना पड़ा था। मुलायम सिंह की रैली तो नहीं हो सकी, लेकिन दर्शन सिंह ने ९ अप्रैल को करहल में इंका की इतनी बड़ी और सफल रैली आयोजित की कि कहा जाने लगा है कि इस क्षेत्र से मुलायम सिंह का असर समाप्त हो गया है।

इस कड़ी में बलराम सिंह यादव ने एटा के असरदार विपक्षी नेता लटूरी सिंह को भी इंका में शामिल करने में सफलता हांसिल कर ली है। इससे बलराम सिंह की रणनीति साफ हो जाती है। स्थान-स्थान पर कांग्रेस-इ की रैलियां आयोजित कर जहां वे कांग्रेस-इ के पक्ष में हवा बनाने की मुहिम में भिड़े हुए हैं, वहीं वे मुलायम सिंह यादव के जमींन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इंका में शामिल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुलायम सिंह से उनके ही घनिष्ठ और असरदार साथी किनारा क्यों करते जा रहे हैं?

मुलायम सिंह का दाहिना हाथ रहे दर्शन सिंह यादव आज उनके साथ नहीं हैं।

मुलायम का भाई-भतीजावाद: दरअसल मुलायम सिंह यादव ने स्थानीय निकायों के चुनावों में अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाया और यही परिवार-प्रेम उनके जनाधार को खोखला करने का कारण बनता जा रहा है। दर्शन सिंह को भरोसा था कि उन्हें इटावा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए लोकदल का प्रत्याशी बनाया जायेगा, लेकिन ऐन मौके पर मुलायम सिंह ने वायदाखिलाफी करके अपने चचेरे भाई प्रोफेसेर राम गोपाल यादव को विकासखंड बसरेहर के ब्लाक प्रमुख पद से इस्तीफा दिलाकर जिला परिषद का अध्यक्ष बनवा दिया। सुभाष यादव मुलायम सिंह से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि मुलायम सिंह ने वायदा करके भी उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनवाने में कोई रुचि नहीं ली। मुलायम सिंह के परिवार-प्रेम का उल्लेख करते हुए सुभाष यादव का कहना है, "अब मुलायम सिंह बसरेहर ब्लाक की खाली सीट पर अपने बहनोई एजेंट सिंह को स्थापित कराना चाहते हैं। मौजूदा समय में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर उनके भाई शिवपाल सिंह, जसवंतनगर ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी में उनके भाई (शिवपाल सिंह) की पत्नी तथा एक अन्य रिश्तेदार हाकिम सिंह यादव, जिला सहकारी बैंक के संचालक हैं।" और यही वजह है कि मुलायम सिंह के खेमे में असंतोष उभरने लगा, जिसका पूरा फायदा बलराम सिंह ने उठाया। अब तो यह कहा जाने लगा है कि जसवतनगर (इटावा) विधानसभा क्षेत्र में दर्शन सिंह यादव ही मुलायम सिंह का मुकाबला करेंगे और मुलायम सिंह को जसवंत नगर सीट छोड़कर भागना पड़ेगा।

दरअसल, १९८० में मुलायम सिंह गुट के छोटे सिंह यादव से कन्नौज के संसदीय चुनाव में हार जाने के बाद बलराम सिंह यादव का मुलायम सिंह से सीधा मुकाबला जसवंतनगर विधानसभा सीट पर हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह हार गये थे, लेकिन मुलायम सिंह का इस क्षेत्र में ऐसा असर था कि १९८५ के विधानसभा चुनाव में श्रीमती गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के बावजूद इटावा की सात विधानसभा सीटों में से चार पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसलिए बलराम सिंह की घेरेबंदी के बावजूद मुलायम सिंह की औकात को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन यह तो वक्त ही बतलायेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा।

बहरहाल, लोकपति त्रिपाठी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सिंचाई विभाग के डाक बंगले के एक सूट पर लगे मुलायम सिंह के ताले को न केवल तुड़वा दिया, बल्कि वहां खड़े रहनेवाले क्रांतिरथ को भी बाहर करवा दिया। सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर मुलायम सिंह का कब्जा इस बात का प्रतीक था कि कांग्रेस-इ मुख्यमंत्री भी उनका दबदबा मानते हैं, लेकिन लोकपति त्रिपाठी ने उनकी यह छवि भी अब धूल में मिला दी है।

—सुरेश द्विवेदी

विज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी

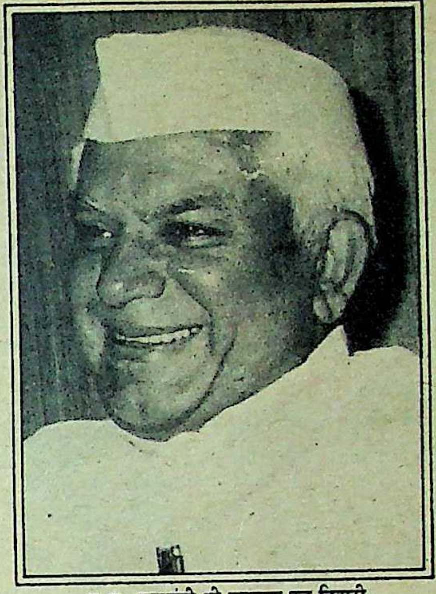

उ०प्र० मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी

पर्वतीय विकास

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचलों की अपनी अनोखी संस्कृति और सभ्यता है। इसको संजोये रखने के साथ इस क्षेत्र का भौतिक दृष्टि से विकास भी आवश्यक है, अन्यथा यह क्षेत्र पिछड़ता चला जायेगा। इस क्षेत्र की विकास समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदेश शासन ने विशेष रणनीति अपनायी है, क्योंकि ये समस्यायें प्रदेश के अन्य भागों की समस्याओं से कहीं अधिक जटिल हैं।

वर्ष १९८९-९० के लिए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए ३००. करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष १९८८-८९ में २७०.५० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी। इस धनराशि में यह बढ़ोतरी सिद्ध करती है कि प्रदेश शासन अपने सीमित साधनों में पर्वतीय विकास के लिए अधिकतम धनराशि की व्यवस्था करता रहा है। यह धनराशि हिमाचल प्रदेश की योजना राशि के समतुल्य है। यह प्रदेश प्रशासन की इस क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता का दूसरा प्रमाण है।

इस धनराशि का उपयोग पर्यटन, फलोत्पादन, वानकी, भूमि संरक्षण, सड़कों एवं पुलों के निर्माण, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, पेयजल, सिंचाई एवं विद्युत, प्रदूषणं रहित उद्योगों आदि की विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन पर किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए अल्मोड़ा तथा श्रीनगर में क्षेत्रीय कार्यालयों ने पहले से कार्य शुरू कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए ऋण उपादान योजना चालू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अनुमन्य ५०,००० रुपए ऋण की सीमा बढ़ाकर २.५० लाख रुपए कर दी गयी है। इस योजना में २० प्रतिशत अनुदान की भी व्यवस्था है।

पर्वतीय क्षेत्र में देशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र को भारत के 'एयर मैप' पर लाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए पिथौरागढ़ में नैनीसैण तथा चमोली में गौचर का चयन किया गया है, जहां हवाई पट्टी का निर्माण किया जायेगा। वहां हेलीकाप्टर सेवा भारत सरकार के उड्डयन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित है।

वर्ष १९८९-९० में तल्लीताल (नैनीताल), घनौल्टी (टिहरी) तथा पूर्णागिरि के पर्यटन आवास गृहों में ९२ अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त गौरीकुंड से गरुड़ चट्टी, लक्ष्मण झूला से कुंजापुरी, राजपुर से मसूरी, ढुलीगाड से पूर्णागिरि तथा हनुमान चट्टी से यमुनोत्री तक रज्जु मार्गों का निर्माण किया जायेगा और जार्ज एवरेस्ट हाउस, मसूरी का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण नगरों में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पेयजल की समस्या के निदान हेतु १०३ करोड़ रुपयों की लागत की ११ परियोजनाएं तैयार की गयी हैं, जिन्हें विश्व बैंक के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

बागवानी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत १० हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में फलोत्पादन, ५,००० हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में फलों के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को पूरा करने का भी प्रावधान किया गया है।

फलों के विपणन को बढ़ावा देने तथा फलोत्पादकों के आर्थिक लाभ के लिए फलों का न्यूनतम मूल्य दिलाने हेतु मूल्य समर्थन योजना भी प्रारम्भ की गयी है। उद्यानों के विकास के लिए भूमि विकास बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों से औद्योगिक विकास ऋण की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन संस्थाओं की ब्याज दरों के अंतर की धनराशि को शासन द्वारा ब्याज अनुदान देकर उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी, ताकि किसानों को परिवर्तित ब्याज दरों से अनुचित भार न पड़े।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में ८,००० हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के उपचार तथा वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग १०,००० हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण एवं चारागाह विकास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है। वानकी विकास कार्यक्रम में औद्योगिक महत्व तथा शीघ्र उगनेवाली प्रजातियों के वृक्षारोपण के अंतर्गत ७.८६ हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य है। पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी बूटियों के विकास के लिए जड़ी बूटी संस्थान खोले जाने की एक योजना तैयार की जा रही है।

सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष १९८९-९० की अवधि में १७४ प्राइमरी स्कूल, ३० जूनियर हाईस्कूल, ८ हाईस्कूल तथा ८ नये इंटर कालेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। त्रिवर्षीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु १० लाख रुपए की नयी योजना लागू की जायेगी। कुल मिलाकर शिक्षा के लिए २५.३० करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा के विस्तार के लिए ६.५ करोड़ रुपए तथा शिल्पकार प्रशिक्षण हेतु ३.२५ करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

सड़कों एवं पुलों के निर्माण को वरीयता दी जा रही है, ताकि जनता को तुरंत इनका लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत १८१ किमी मोटर मार्गों का निर्माण, २३५ किमी मोटर मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार, १२ मोटर मार्ग पुल तथा ४० पैदल पुलों का निर्माण किया जायेगा। इन कार्यों के लिए ४० करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत ५२८ ग्रामों में एवं त्वरित ग्रामीण पेय जल योजना के अंतर्गत १२२ ग्रामों मे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर वार्षिक योजना (८९-९०) के अंतर्गत ३३ करोड़ रुपए व्यय होंगे।

चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए चार एलोपैथिक औषधालय तथा १९ नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जायेगी, जिन पर ९ करोड रुपए व्यय होने का अनुमान है।

लघु सिचाई योजनाओं से लगभग १७३०० हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिचन क्षमता का सृजन किया जायेगा। सिचाई के लिए १७.३७ करोड़ रुपए तथा ग्रामीण एवं हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए ३२.३५ करोड रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का भी विकास किया जायेगा, जिस पर १.५ करोड़ रुपए व्यय किये जायेंगे।

पर्वतीय क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्ट्रानिक उद्योग को विशेष रूप से बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सात इलेक्ट्रानिक उद्योग आस्थान, दो इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र तथा नयी टिहरी में टीवी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता समितियों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा आर्थिक विकास हेतु वस्त्र-शिल्प, जड़ी-बूटी, इलेक्ट्रानिक्स लघु उद्योगों के समन्वित विकास के लिए एक आयोग गठित किया गया है, जिसके अंतर्गत एक लघु एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य कार्यालय श्रीनगर में एवं एक उप कार्यालय अल्मोड़ा में खोला जायेगा।

पशुपालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं की नस्लों के सुधार के साथ-साथ चारा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीनगर (गढ़वाल) में २०,००० लीटर क्षमता की एक दुग्धशाला स्थापित की जायेगी। देहरादून तथा लाल कुआं दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की वर्तमान दुग्ध क्षमता को १०,००० लीटर से बढ़ाकर २०,००० लीटर प्रतिदिन कर दिया जायेगा।

इस क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर विहंगम दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र की विशेष समस्याओं के निदान के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही योजनाएं बनायी गयी हैं। प्रदेश प्रशासन ने इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर यह सिद्ध कर दिया है कि इस क्षेत्र के सम्यक् विकास के लिए वह बहुत अधिक प्रयत्नशील है।

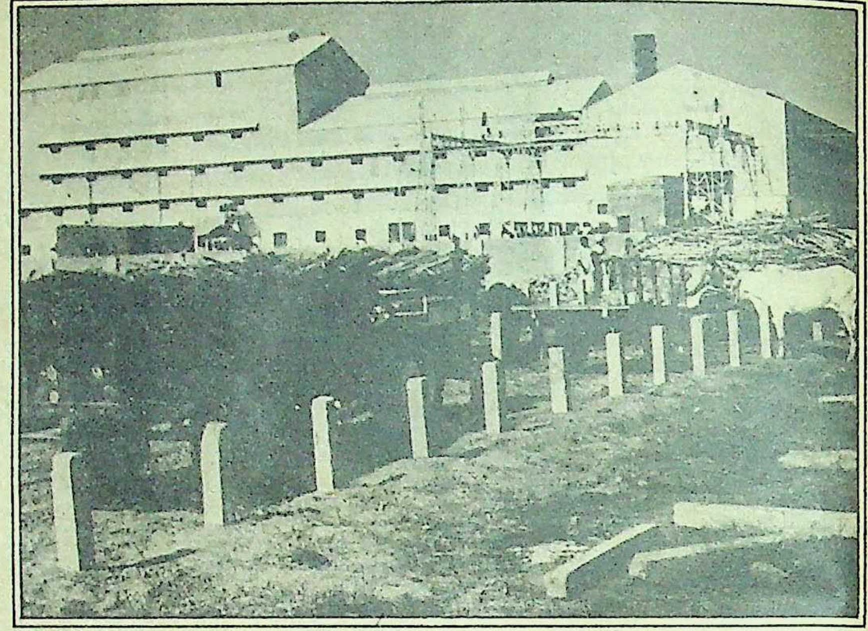

चीनी मिल, सितारगंज, नैनीताल

गरीबों के लिए ढाई लाख मकान

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मकानों के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के गरीब व निर्बल वर्गों के लिए ढाई लाख मकान बनाने का काम शुरू हो गया है। इस व्यापक योजना के तहत एक लाख ९५ हजार लाभार्थियों का चयन भी कर लिया गया है। इस आवास योजना पर सवा अरब रुपए खर्च होंगे। इस काम के लिए अभी तक बैंकों से चालीस करोड़ रुपए ऋण के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को कितनी तरजीह दे रही है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पिछले चालीस वर्षों में प्रदेश में कुल दो लाख चालीस हजार मकान बने हैं, वहीं इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई चरणों में ढाई लाख मकान बनाने की महती योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।

इन ग्रामीण आवासों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। काम की प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि २० हजार गांवों का चयन किये जाने के साथ ही १७ हजार लाभार्थियों के लिए निर्माण समूहों का गठन भी किया जा चुका है। योजना के तहत ९२ हजार ६५८ मकानों का निर्माण प्रथम चरण में शुरू हो चुका है। इनमें से ३५१८ मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी ने जब इस आवासीय योजना की बात शुरू की थी, तब ऐसा लगता था कि यह योजना वर्षों तक चलेगी। परंतु अब मकानों के निर्माण की प्रगति को देखकर यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि इतनी बड़ी आवासीय योजना का लक्ष्य पूरा करके मुख्यमंत्री ने असभव को संभव कर दिखाया है। इस सभी आवासों के मार्च के अंत तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है।

इस ग्रामीण आवासीय योजना के अधीन मैदानी क्षेत्रों में ६ हजार रुपए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ७८०० रुपए की लागत से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निर्बल वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं। इन मकानों पर मैदानी क्षेत्र में ४००० रुपए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ५८०० रुपए अनुदान राशि होगी। शेष राशि ४ प्रतिशत के सस्ते ब्याज पर बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

अगर हम मकानों की लागत को देखें, तो मैदानी क्षेत्रों व पर्वतीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को ये मकान मात्र २,००० रुपए में मिल सकेंगे। इतने सस्ते मकान प्रदेश के इतिहास में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा निर्बलवर्ग के लोगों को इससे पहले कभी नहीं मिले। प्रदेश के निर्बलवर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत भी ५०,००० भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

हाल ही मुख्यमंत्री ने हुड्को के अध्यक्ष से शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मकानों की कमी को पूरा करने के लिए और अधिक ऋण लेने के संबंध में बात की थी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मकानों के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसे देखते हुए हुड्को को ग्रामीण

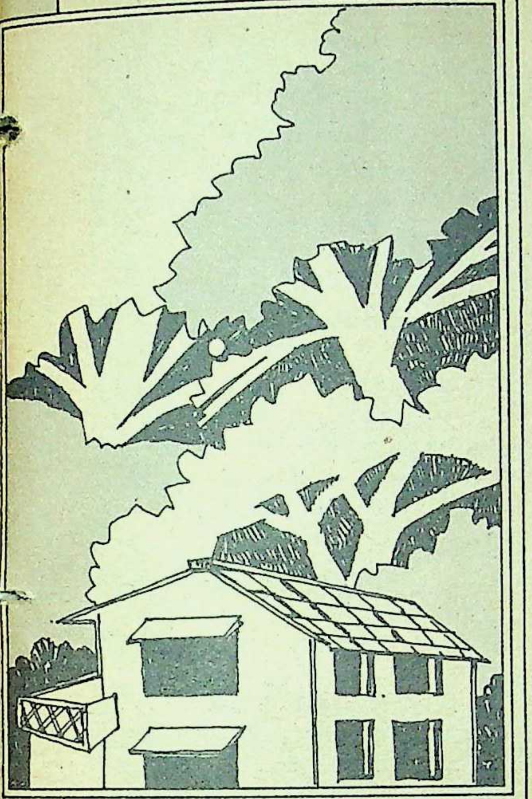

क्षेत्रों में विशेषकर भूमिहीन मजदूरों के लिए और अधिक ऋण देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि बुनकरों, हथकरघा कर्मचारियों व बीड़ी मजदूरों के लिए भी आवास योजनाएं बनायी जानी चाहिए।

हुड्को के अध्यक्ष श्री एसके शर्मा के अनुरोध पर शहरी आवास एजेंसियों द्वारा लिये जाने वाले ऋण की गारंटी लेना भी प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश इस तरह का निर्णय लेने वाला पहला प्रदेश है, इससे हुड्को द्वारा विभिन्न आवास एजेंसियों को ऋण देने मे काफी सहूलियत होगी।

सहकारी समितियों को विशेषकर सरकारी कर्मचारियों की सहकारी समितियों को अब बड़े पैमाने पर आवास ऋण मिल सकेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों व हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिये हैं कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाये।

एक ओर जहां आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर भवन-निर्माण-कार्य में लगे लोगों को प्रशिक्षित किये जाने व प्रचुर मात्रा में भवन-निर्माण-सामग्री उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा रही है। शहरी विकास विभाग मंडलीय मुख्यालयों पर ग्यारह ऐसे केंद्र खोलेगा, जहां मिस्त्रियो को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी तरह के तीन केंद्र ग्रामीण क्षेत्रो में भी खोले जायेंगे।

नोएडा, गाजियाबाद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गठित औद्योगिक इस्टेटों की तरह कई स्थानों पर भवन-निर्माण-सामग्री इस्टेट भी गठित किये जायेंगे, जहां नयी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भवन-निर्माण-सामग्री तैयार की जायेगी। तीनों विकास प्राधिकरण भवन-निर्माण सामग्री बाजार का भी निर्माण करेंगे, जिससे इच्छुक लोगों को एक ही बाजार में सारा सामान मिल सके। इन बाजारों में भवन-निर्माण-सामग्री का धंधा करने वाले लोगों को जगह भी उपलब्ध करायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरण आवास मार्गदर्शन केंद्र भी खोलेंगे, जहां से जमीन खरीदने व मकान बनवाने संबंधी सूचनाएं जनसामान्य को प्राप्त हो सकेंगी। मुख्यमंत्री यह भी चाहते है कि तेजी से बढ़ रहे नगरों व महानगरों के आसपास छोटे-छोटे शहर भी बसाये जायें, ताकि इन बड़े शहरों की आवास व्यवस्था का बोझ कुछ कम हो सके। उन्होंने इस संबंध में हुड्को द्वारा पेश की गयी योजना पर पूरी गंभीरता से अमल किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। नये शहरों को बसाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से मदद लेने पर भी विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में शहरी विकास कार्य कितनी तेजी से चल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष १९८७-८८ में पूरे देश में हुड्को ने सबसे ज्यादा ऋण उत्तर प्रदेश को ही दिया था। न केवल शहरी विकास के लिए, बल्कि आवास निर्माण के लिए भी उत्तर प्रदेश ने हुड्को मे सर्वाधिक

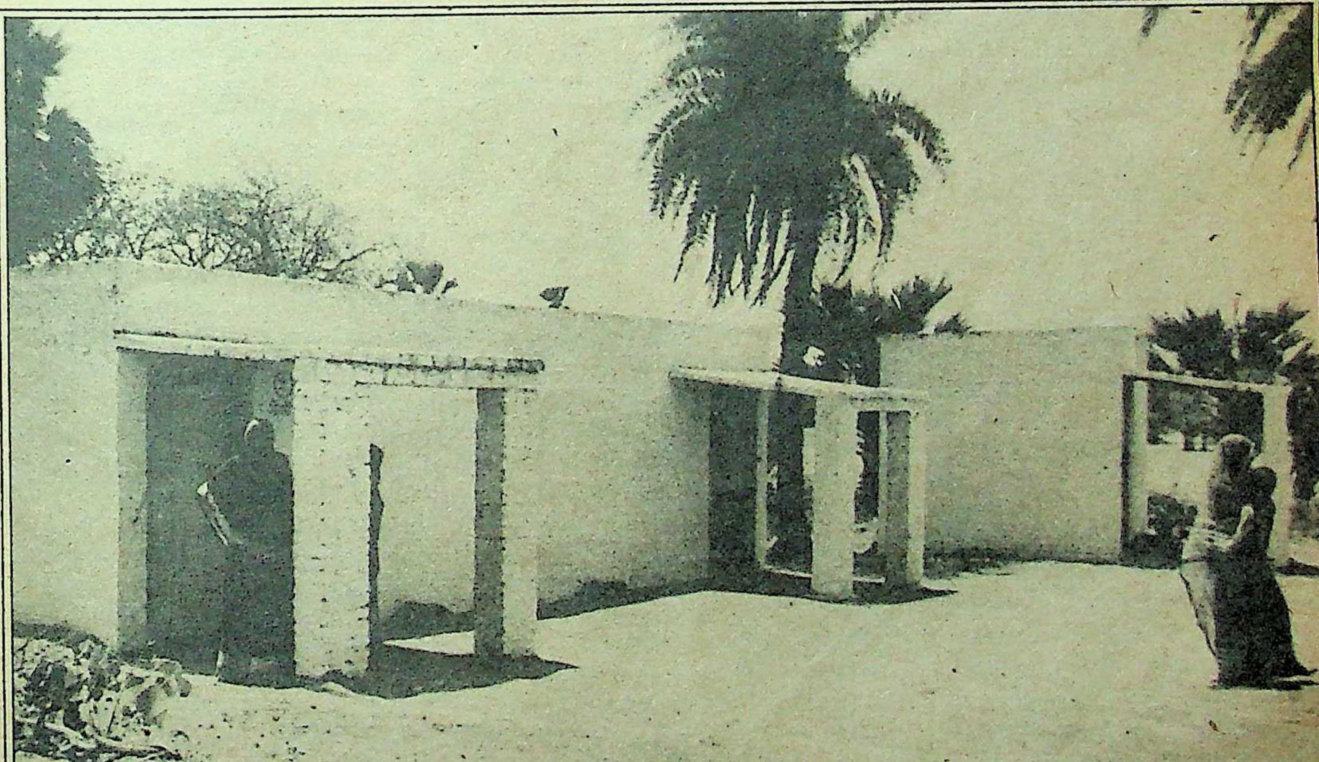

गरीब एवं निर्बल वर्ग के लिए ग्रामीण आवास योजना

Digitiz Chennai and eGangotri

ऋण प्राप्त किया।

सामान्य जनता के अतिरिक्त प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों के लिए भी बड़े पैमाने पर मकान बनवा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के थानों के पुलिसकर्मियों की आवास व्यवस्था सुधारने के लिए भी मकान बनवाने का निश्चय किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रयास के फलस्वरूप हुड्को ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों के आवास निर्माण के लिए कम ब्याज पर ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

इस प्रकार पूरे प्रदेश में न केवल बड़े पैमाने पर आवास निर्माण का कार्य चल रहा है, बल्कि आबादी सुधार कार्यक्रम के तहत बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है। जनसुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हाल ही मेरठ जिले के लतीफपुर और सरद्धानी गांव में ग्रामीण आबादी सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण आवास परिषद द्वारा तैयार की गयी योजना के लिए हुड्को से ऋण भी प्राप्त हुआ है। ●

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम

देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के अपेक्षित लाभ उस समय तक बाधित रहते हैं, जब तक कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाता। बढ़ती हुई आबादी हमारे संसाधनों और उनके अधिकतम उपयोग और लाभ पर अंकुश का काम करती है और ऐसी भी स्थिति पैदा कर देती है, जबकि विकास और प्रगति नगण्य प्रतीत होने लगती है।

भारत में बढ़ती हुई आबादी का अभिशाप बढ़ता जा रहा है। सन् १९५१ में देश की जनसंख्या ३६.५१ करोड़ थी जो वर्ष १९८१ में बढ़कर ६८.३८ करोड़ हो गयी। इस तथ्य से जनसंख्या वृद्धि का वेग स्पष्ट है और उसे रोकने की आवश्यकता उजागर होती है। परिवार को सीमित रखकर जनसंख्या के इस बढ़ते हुए वेग को रोकने के उद्देश्य से वर्ष १९५२ से पूरे देश में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

उत्तर प्रदेश में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अलावा अन्य विभागों के सहयोग से पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर किया जा रहा है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क, प्रचार-प्रसार, शिक्षा और प्रेरणा द्वारा लक्ष्य दम्पतियों को अपने परिवार को छोटा रखने के लिए परिवार परिसीमन की कोई भी विधि स्वीकार करा दी जाती है। इस कार्यक्रम को जोर-जबरदस्ती या दबाव का सहारा लिये बगैर स्वैच्छिक आधार पर एक जन आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत चिकित्साधिकारी

हाल में भारत सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुरूप इस कार्यक्रम को अन्य विकास कार्यक्रमों में सन्निहित करके महिला शिक्षा, समांज सुधार, पोषण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम को और व्यापक तथा प्रभावी बनाने पर बल दिया जा रहा है। कार्यक्रम को अधिकाधिक लोकप्रिय और सर्वग्राह्य बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों के क्षेत्रस्तरीय तथा वरिष्ठ अधिकारियों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है।

परिवार परिसीमन विधियों एवं साधनों को लक्ष्य दम्पतियों के आवास के निकट सुलभ कराने के लिए बहुस्तरीय विशिष्ट सेवा शिविरों का बड़ी संख्या में आयोजन किया जाता है। जनसेवा तथा स्वैच्छिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थानीय साधन व सेवाकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहनस्वरूप उपहार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य से ग्राम्य स्तर तक श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामप्रधानों, ब्लाक प्रमुखों समेत अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए आकर्षक पुरस्कार योजनाओं को लागू किया गया है। इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा अनेक स्तरों पर की जाती है, जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहे और निर्धारित मानकों का पालन होता रहे। संसाधनों एवं वित्तीय प्रावधानों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाती रही है।

परिवार कल्याण के संदेश को सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया है। राज्य स्तर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक सूचना, शिक्षा एवं संचार इकाइयां स्थापित की गयी हैं। इन इकाइयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत संपर्क के अलावा सामूहिक बैठकें और सभाएं आयोजित की जाती हैं। पोस्टरों और विज्ञापनों के अतिरिक्त नाटक, नौटंकी, भजन, कव्वाली कठपुतली और वरायटी-प्रोग्रामों के माध्यम से सीमित परिवार के लाभों एवं उपायों से जनसामान्य को अवगत कराकर उन्हें प्रेरित किया जाता है।

नगरीय क्षेत्रों की हरिजन एवं मलिन बस्तियों में परिवार कल्याण सेवाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण के लिए अर्बन रिवैम्पिंग योजना प्रदेश के १७ जनपदों में लागू की गयी है। ये जनपद हैं : इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, झांसी मुरादाबाद, गोरखपुर, देहरादून तथा फिरोजाबाद।

परिवार कल्याण कार्यक्रम से अभिन्न रूप से महिला और शिशु कल्याण तथा प्रसवोत्तर कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। तद्नुसार इस पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वस्तुत: परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता भी बहुत कुछ इन्हीं सेवाओं पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती माताओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए नि:शुल्क टीके लगाये जाते हैं और नि:शुल्क औषधियां दी जाती हैं। बच्चे के जन्म के समय से ही उन्हें अच्छी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित दाइयां गांवों में नियुक्त की गयी हैं। माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्र की महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री तथा महिला स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। बच्चों को छ: भयानक रोगों से बचाव के टीके नि:शुल्क दिये जाते हैं। रोगों से प्रतिरक्षण के एक सर्वव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव के टीके तथा जन्म से १२ माह की आयु के ८५ प्रतिशत शिशुओं को छ: बीमारियों से बचाव के टीके लगाने का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता और उसके प्रयासों के बारे में किसी भी वर्ग, जाति, संस्था या संगठन में अब लेशमात्र भी मतभेद नहीं है। हमारे समाज का हर व्यक्ति व समुदाय इस तथ्य से भली प्रकार सहमत है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस कार्यक्रम का सफल होना नितांत आवश्यक है। इसी विश्वास, दृष्टिकोण और जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम निष्ठापूर्वक संचालित किया गया। परिणामस्वरूप प्रदेश में विगत तीन वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्यों की उपलब्धि का स्तर ऊपर उठता गया और वर्ष १९८६-८७ में तो सभी क्रियाकलापों में शत-प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल हुई। प्रदेश ने वर्ष १९८५-८६ तथा १९८६-८७ में अपने ग्रुप में परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पाने के फलस्वरूप भारत सरकार से २.५० करोड़ रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया। वर्ष १९८७-८८ में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने पर २.५० करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। विगत तीन वर्षों तक प्रदेश श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाता रहा। आशा है कि वर्ष १९८८-८९ में भी यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस वर्ष गत दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत नसबंदी में ८०.६७ प्रतिशत, लूप निवेशन में ११६.६१ प्रतिशत, निरोध प्रयोग में ८९.७९ प्रतिशत, तथा ओरल पिल्स प्रयोगकर्ता की मद में १३७.१८ प्रतिशत उपलब्धियां विशेष उल्लेखनीय हैं। ●

ये ज़िंदगी के हसीन पल.
QUARTZ

एचएमटी क्वार्ट्ज़. एक से एक शानदार किस्में इलेक्ट्रॉनिक क्वार्ट्ज़ घड़ियों की. समय का वो साज़ जिस पर आपको नाज़. आपकी राह में ज़िंदगी की हसीन घड़ियां.

hmt
QUARTZ

everest/S89/245

अब निशाने पर जगन्नाथ

बिहार प्रदेश कांग्रेस-इ का अध्यक्ष बनने के बाद जगन्नाथ मिश्र को किन बवंडरों से जूझना पड़ रहा है ?

"जगन्नाथ का भी सचमुच जवाब नहीं। पहले सबको दरी पर बुलाकर बिठाया और फिर दरी उलट दी। इसलिए मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इस जगन्नाथ को राजनीति में कोई उलट नही सकता। आज यह सबके सीने पर सवार है।" अभी पिछले दिनों इंका के अलमस्त राष्ट्रीय खजांची सीताराम केसरी जब यह वक्तव्य देकर अचानक अपनी अदा में नाखून कुरेदते हुए जोरों से ठठाकर हंस पड़े, तो पटना में उनके युवा इंकाई चेलों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। केसरी शायद इस बात को ताड़ गये, सो और अधिक खुलासा करते हुए वे शुरू हो गये—"अरे भाई, हमारे बाबा (बिंदेश्वरी दुबे) फिर बिहार की गद्दी का सपना देखने लगे थे और यहां तक कि हमारे तारिक मियां भी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में बेहाल थे। ललितेश्वर शाही भी बेचैन थे। बस जगन्नाथ ने इन लोगों को एक दरी पर बुलाकर बिठाया और दरी उलटकर सबके ऊपर बैठ गये।" केसरी फिर अचानक अपनी टोपी तिरछी करते हुए जोरों से खिलखिला उठे और बोले—"हां, एक फायदा हुआ। टोपीवाला (सत्येंद्र नारायण सिह) मुख्यमंत्री बन गया। राजीवजी ने टोपी की लाज रख ली।" बहरहाल, केसरी कुछ सेकेंड तक अपनी टोपी माथे पर टेढ़ी-सीधी करते हुए इसी वाक्य को गुनगुनाते हुए झूमते रहे और फिर एक बारगी गंभीर हो उठे—"जो लोग कहते हैं कि मैं जगन्नाथ से मिल गया हूं, वही लोग जगन्नाथ की गाली पढ़ते-पढ़ते जोर-शोर से आरती उतार रहे हैं। मैंने तो बस एक चवन्नी डालकर आरती को प्रणाम भर किया।" केसरी की ये बातें वहां उपस्थित युवा इंकाइयों को असंगत तो जरूर लग रही थीं, पर दिलचस्प अवश्य। इसलिए केसरी की खिलखिलाहट में सब-के-सब घंटों से सुर मिला रहे थे। केसरी की यही विशिष्टता है कि गंभीर से गंभीर बात को मजाक की शैली में सहजता से कह जाते हैं।

जगन्नाथ मिश्र को लेकर इन दिनों बिहार के कांग्रेसी दिग्गजों में जिस तरह की बेचैनी है, वह बहुत अस्वाभाविक भी नहीं। यह बेचैनी विशेषकर दो किस्म के कांग्रेसी नेताओं में है। एक तो वे लोग, जिन्होंने गुजरे पांच-छह वर्षों में सत्ताच्युत जगन्नाथ मिश्र की रही-सही चटाई भी उलटने की कोशिश की और दूसरे वे लोग जिनकी दरी उलटकर जगन्नाथ मिश्र चुनाव वर्ष में बिहार में कांग्रेस के नियंता बन बैठे हैं। इस तरह जगन्नाथ मिश्र के विरुद्ध दो किस्म के कांग्रेसी नेता वर्जिश कर रहे हैं। लिहाजा, जगन्नाथ से नाराज और जगन्नाथ से सशंकित लोगों का समीकरण बन जाना लाजिमी है। संभवतः इन्हीं कारणों से विक्षुब्ध गतिविधियों की सुगबुगाहट मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के विरुद्ध अब तक किंचितमात्र भी परिलक्षित नहीं हो रही है, लेकिन जगन्नाथ मिश्र निशाना बने हुए हैं। बिहार राजनीति के एक वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ कहते हैं कि आज तक कांग्रेस के इतिहास में यहां कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था कि विक्षुब्ध गतिविधियां मुख्यमंत्री के बजाय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चली हों।

घेरे में : वाकई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में डा० जगन्नाथ मिश्र बवंडर के घेरे में हैं। पर इस स्थिति में पहले की भांति वे बौखलाते नहीं, बल्कि शांत और संयत हैं। पहले जब सीधे इंका आलाकमान से उनकी ठनी हुई थी और उन पर चौतरफा प्रहार हुआ करता था, तो झल्लाहट में वे भी बढ़-चढ़कर प्रहार किया करते थे। पर अब जबकि वे बदली हुई भूमिका में हैं, तो उनके प्रहार की शैली मुखर न होकर मौन हो गयी है। जगन्नाथ मिश्र का यह मारक मौन उनके विरोधियों की जमात को परेशान किये हुए है। इसलिए उनके विरोधी उन्हें पहले की भांति बौखलाया हुआ देखने के लिए अहर्निश प्रयास में हैं।

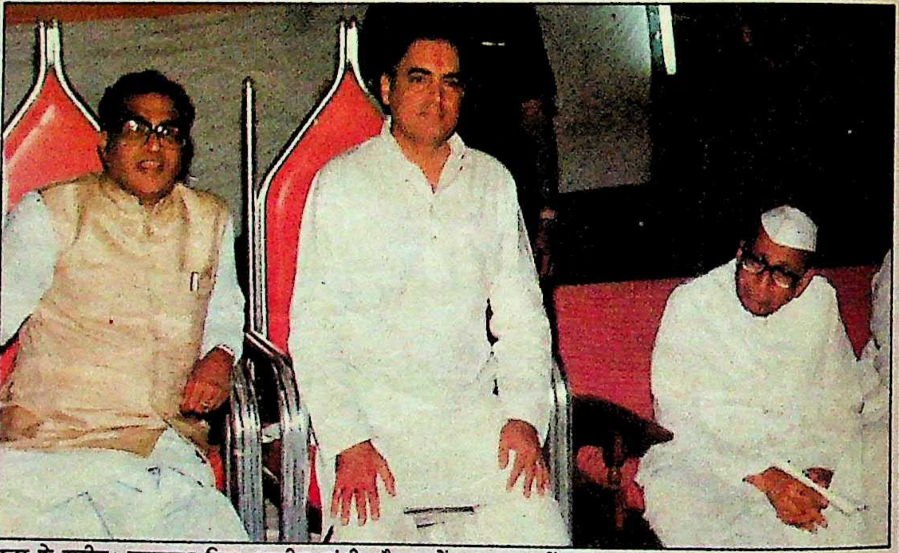

सत्ता के करीब : जगन्नाथ मिश्र, राजीव गांधी और सत्येंद्र नारायण सिंह

फिलहाल, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने जगन्नाथ मिश्र पर जबर्दस्त ढंग से हमला बोल रखा है। गुजरे महीनों में तारिक ने जगन्नाथ के विरुद्ध दरभंगा से लेकर समस्तीपुर सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर तक सभाएं कर उनको आड़े हाथों लिया है। जगन्नाथ मिश्र को परेशान करने के लिए ही तारिक ने भी बिहार में जगन्नाथ शैली का जनजागरण करने की मुनादी कर दी है। ३ मई को तब स्थिति विचित्र हो गयी, जब जगन्नाथ मिश्र पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आयोजित पटना प्रमंडलीय कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। अचानक हाल में अफरातफरी मच गयी और जगन्नाथ मिश्र विरोधी नारे तेज हो गये। नारे लगानेवाले अधिकांश लोग सेवादल के थे। बिहार सेवादल के अध्यक्ष करुणेश्वर सिंह तारिक अनवर के प्रमुख सिपहसालार हैं। इसलिए स्पष्ट हो गया कि तारिक-खेमा जगन्नाथ मिश्र के विरोध में किस तरह कमर कस कर उतरा हुआ है। २३ अप्रैल को दरभंगा में आयोजित जिला सेवादल के कार्यक्रम में तारिक अनवर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। बिलकुल जगन्नाथ-शैली में ही तारिक के स्वागत की दरभंगा में तैयारी की गयी। दरभंगा सेवादल की बैठक में भी तारिक ने जगन्नाथ मिश्र की जमकर आलोचना की और आरोप लगाया कि कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वे उपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही यह कहकर कि उनके मुख्यमंत्रित्वकाल के बाद प्रदेश में किसी सरकार ने एक इंच विकास नहीं किया, जगन्नाथ मिश्र सीधे-सीधे कांग्रेस को परोक्ष रूप से आहत कर रहे हैं। क्योंकि उनके इस वक्तव्य पर लोग चुनाव में उनसे पूछ सकते हैं कि तब हम कांग्रेस को वोट क्यों दें, जब कांग्रेस ने पिछले पांच-छह वर्षों में कुछ किया ही नहीं। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विनोद नारायण झा दिल्ली से सीधे मधुबनी आये और प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि जगन्नाथ मिश्र कम-से-कम अब भी यह कहना बंद कर दें कि उनके बाद बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। भागवत झा आजाद जब तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज थे, तब तक तारिक अनवर जगन्नाथ मिश्र की हां-में-हां मिलाते थे। पर

जब जगन्नाथ उन्हीं की गद्दी पर काबिज हो गये और सत्येंद्र नारायण सिंह मंत्रिमंडल में उन्हें बतौर काबीना मंत्री शामिल करवाने का भी इंतजाम कर दिया, तो तारिक बुरी तरह जगन्नाथ मिश्र पर बिफर उठे। दरअसल, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद तारिक ने बिहार के अल्पसंख्यकों के बीच थोड़ी पैठ बनायी, जिससे जगन्नाथ मिश्र का सशंकित होना स्वाभाविक था। अब तक मैथिल ब्राह्मणों का नेता होने के साथ-साथ उनका दावा था कि वे अल्पसंख्यकों के भी बिहार में रहनुमा हैं। पर अल्पसंख्यकों के बीच तारिक की घुसपैठ बढ़ती देख जगन्नाथ मिश्र परेशान हुए। लिहाजा, तारिक की राजनीतिक औकात कम करने के लिए उन्होंने पलीता बिछाना शुरू कर दिया। पर तारिक ने थोड़ी हिम्मत दिखायी और सत्येंद्र-मंत्रिमंडल में शपथ न लेकर साबित कर दिया कि राजनीति में महज वे लकदक और नफीस-से दीखनेवाले राजनीतिज्ञ नहीं हैं, बल्कि घात-प्रतिघात झेलने का भी माद्दा रखते हैं। ३ अप्रैल को बिहार के अल्पसंख्यकों में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की खातिर तारिक ने पटना में 'बिहार प्रदेश कौमी तंजीम' नामक संगठन के तत्वावधान में सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में उनके पत्रकार मित्र एमजे अकबर और शाहिद सिद्दीकी भी शामिल हुए। तारिक खेमा यह बात जोर-शोर से प्रचारित करने में जुटा है कि जगन्नाथ मिश्र ने तो सदैव अल्पसंख्यकों की कीमत पर गद्दी पायी है। मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें अब्दुल गफूर को हटाकर मिली थी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी तारिक अनवर को अपदस्थ कर।

मुठभेड़ की नौबत : तारिक अनवर और जगन्नाथ मिश्र

आजाद-जगन्नाथ-द्वंद्व : पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद से भी जगन्नाथ मिश्र के ठनने की संभावना ने जोर पकड़ा था। २० अप्रैल को बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के पटना में आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन भागवत झा आजाद ने जब अपने भाषण में जगन्नाथ मिश्र की जमकर खिंचायी की, तो राजनीतिक पंडितों को लगा कि अब इन दोनों दिग्गज मैथिल नेताओं में कसकर भिड़ंत होगी। युवक कांग्रेस के सम्मेलन में आजाद ने कहा कि मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने कभी कांग्रेस के समानांतर दूसरी संस्था खड़ी कर कांग्रेस को कमजोर नहीं किया। आजाद का इशारा जगन्नाथ मिश्र द्वारा अभी भी चलाये जा रहे संगठन 'जन विकास मंच' की ओर था। इस मौके पर तारिक अनवर भी उपस्थित थे। तारिक ने कहा कि जिन नेताओं ने कल तक कांग्रेस आलाकमान को गालियां दीं, आज वही कुरसी पाकर तारीफ के पुल बांध रहे हैं। ऐसे नेताओं की निष्ठा आलाकमान से नहीं, कुरसी से है। बहरहाल, आजाद जगन्नाथ मिश्र से दो-दो हाथ करने की मुद्रा में पूरी तरह तैयार थे। पर मई के पहले सप्ताह में जब आजाद पटना आये, तो जगन्नाथ मिश्र अचानक आजाद के निवास पर जा पहुंचे। जगन्नाथ मिश्र का आना आजाद के लिए भी अप्रत्याशित था, क्योंकि दो-तीन दिन पूर्व पटना में आयोजित कुंवर सिंह जयंती के एक कार्यक्रम में इत्तफाक से आजाद व जगन्नाथ दोनों आमंत्रित थे। पर ये दोनों नेता एक-दूसरे से कटे-कटे रहे। जगन्नाथ मिश्र ने आजाद से मिलकर नाराजगी भूल जाने का अनुरोध किया। आजाद राजनीति में जगन्नाथ मिश्र के अग्रज स्व० ललितनारायण मिश्र के ही समकालीन रहे हैं। लिहाजा, जगन्नाथ मिश्र ने आजाद से कहा कि बड़े भाई के नाते वे उनकी मदद करें। बहरहाल, जगन्नाथ की मुलाकातों और मिन्नतों से आजाद जगन्नाथ के प्रति कितने सहज हुए, यह तो आनेवाला समय ही बतायेगा। पर जगन्नाथ मिश्र जो अध्यक्ष बनने के बाद आजाद के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे, को आखिरकार लगा कि बिहार में स्वच्छ छवि स्थापित कर चुके इस मैथिल नेता से अदावत मोल लेकर सिवा परेशानी के उन्हें कुछ हासिल नहीं होने का। आजाद ने अप्रैल के मध्य में दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर पटना लौटने के बाद ऐलान किया था कि वे बिहार में पदयात्रा करेंगे। पर फिर आजाद ने उसे स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे विवाद बढ़ सकता है। अलबत्ता, आजाद ने अपनी पदयात्रा अभियान के मुल्तवी करने घोषणा नहीं की है।

'बिहार जन विकास मंच' के अस्तित्व को लेकर भी जगन्नाथ मिश्र का कम विरोध नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जगह-जगह यह शिकायत कर रहे हैं कि 'बिहार जन विकास मंच' के पदाधिकारी हर जगह कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकताओं को परेशान कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र अभी भी इस मंच के अध्यक्ष बने हुए हैं। लिहाजा, इस बात को जोरों से कहा जा रहा है कि दोहरी सदस्यता का चक्कर नहीं चलेगा। जगन्नाथ के आलोचक आरोप लगाते हैं कि जगन्नाथ मिश्र 'जन विकास मंच' व कांग्रेस की दोहरी सदस्यता एक साथ चलवा रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जहां-जहां पिछले दिनों सभा करने पहुंचे हैं—'दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी' की नारेबाजी उन्हें झेलनी पड़ी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन अब तक न होना भी अटकलों को गर्म किये हुए हैं। विगत १० अप्रैल को ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार मामलों के प्रभारी एआर मल्लू ने कहा कि यथाशीघ्र प्रदेश की कमेटी बन जायेगी। पर यह रपट लिखे जाने तक कमेटी नहीं बन सकी है।

मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह से जगन्नाथ मिश्र के संबंध कैसे चल रहे हैं, इसको लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता है। लगभग दो माह पूर्व पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की एक बैठक में सत्येंद्र नारायण सिंह भी आये। इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक व मंत्री आमंत्रित थे। जगन्नाथ मिश्र जब भाषण के लिए खड़े हुए, तो पहले कुछ देर तक उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिंह की तारीफ की और फिर तुरंत अपनी पुरानी पटरी पर आकर गिनाने लगे कि किस तरह बिहार में हरिजन, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को तबाही झेलनी पड़ रही है। सत्येंद्र नारायण सिंह भांप गये कि जगन्नाथ अपना वही मारण-मंत्र उन पर भी चलाने जा रहे हैं जो अब तक वे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर चलाते रहे हैं। लिहाजा, सत्येंद्र नारायण सिंह के बोलने की जब बारी आयी, तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मिश्र ने अपने भाषण में क्या कहा, यह वे माइक की खराबी के कारण नहीं सुन सके। अगर कोई समस्या उन्हें हो, तो वे लिखकर दिया करें। सत्येंद्र नारायण सिंह के इस कूटनीतिक वक्तव्य की जबर्दस्त चर्चा रही। बिहार के राजनीतिक पंडित निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि अभी, जबकि खुद जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ बवंडर के आसार बने हुए हैं, ऐसे में सत्येंद्र नारायण सिंह से टकराकर वे दलदल में फंसना नहीं चाहते। वैसे भी जगन्नाथ-खेमा आश्वस्त है कि सत्येंद्र तो बस चुनाव तक के लिए ही गद्दी पर हैं, आखिरकार चुनाव के बाद सत्ता जगन्नाथ मिश्र को ही संभालनी है, तो सत्येंद्र से लड़ने का क्या लाभ?

—विकास कुमार झा

नाम की सनक

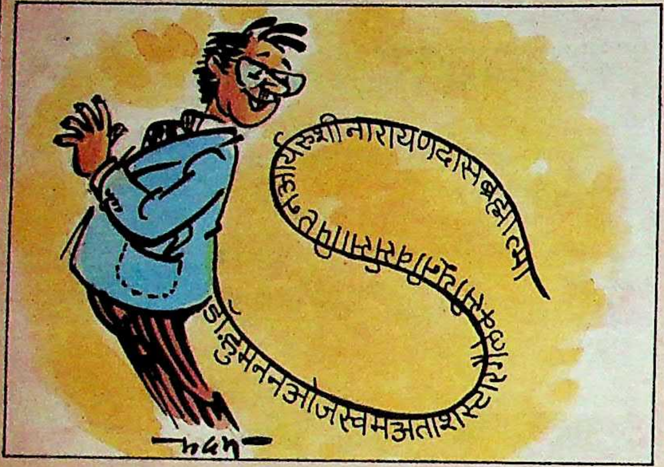
डा०हुमननओजस्वमअताशस्टारगेलेक्सीयूनीवर्ससैपियनआर्यरूबीनारायणदासब्रह्मात्मा

वैसे तो किसी के नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो अपने नाम के भरोसे ही फूलते-पचकते रहते हैं। जबकि असलियत यह है कि नाम भी काम ही से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जो लंबा नाम रखकर ही नामवरी चाहते हैं। अहमदाबाद निवासी डा० मनोज नारायणदास सोनी साहब भी ऐसे ही हैं जिन्होंने लगभग चार इंच लंबा नाम रखा है। उनका नाम लेकर उनको बुलाना तो कठिन है, लेकिन लिखा कुछ यों जा सकता है : 'डाक्टर हुमननओजस्वमअताशस्टारगेलेक्सीयूनीवर्ससैपियनआर्यरूबी-नारायणदास ब्रह्मात्मा'। उनका कहना है कि अभी तक 'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स' में जिस सबसे लंबे नाम का उल्लेख है, उसमें ३६ अक्षर हैं, जबकि मेरे नाम में ४८ अक्षर हैं। यों तो उन्होंने अपना नामकरण आठ महीने पहले किया था, लेकिन पिछली १६ जनवरी '८६ को उनका नाम महाराष्ट्र सरकार के गजट में दर्ज किया गया। डा० सोनी गिनीज बुक में अपने नाम को दर्ज कराने की भी मांग कर रहे हैं, देखना है, वे कब सफलता प्राप्त करते हैं।

बंदरिया जो सौतन बनी

कितनी ही ऐसी औरतें हैं, जो लाख बुराइयों के बाद भी अपने आदमियों के लिए जान देने को आतुर रहती हैं। यदि पति नालायक है, नामाकूल है, दारूबाज है, लैमर है, चोर-उच्चका है, तो भी वह उसके लिए परमपूज्य है, आदर्श है। कहने का अर्थ यह कि औरत सब कुछ बरदाश्त कर सकती है, लेकिन उसे यह मालूम हो जाये कि उसका मर्द किसी और औरत से संबंध रखता है, तो वह उसकी जान लेने पर भी उतारू हो सकती है।

लेकिन कोई पत्नी एक बंदरिया के लिए अपने पति को तलाक देने पर उतारू हो जाये, तो बात कुछ अटपटी-सी लगती है। लेकिन तेलअबीव की एक महिला ने इसी बिना पर अपने पति को तलाक देने के लिए आवेदन कर रखा है। उसका आरोप है कि उसका पति हर समय उसका नहीं, बल्कि अपनी बंदरिया का मुंह देखना पसंद करता है और दिन-रात बंदरिया के नखरे उठाने में लगा रहता है। उसका कहना है, "यह बंदरिया नहीं, बल्कि मेरी 'सौतन' है जिसने मेरा पति मुझसे छीन लिया है। मैं अपने पति और बंदरिया के साथ एक पल भी नहीं गुजारना चाहती।" उसने तलाक के लिए जो आवेदन किया है, उसमें उसने मांग की है कि उसे दो हजार डालर मासिक गुजारा भत्ता दिया जाये, साथ ही उसके घर से उसके पति और उसकी बंदरिया सौतन को बाहर निकलवा दिया जाये।

जब बंदरों ने आरकेस्ट्रा आयोजित किया

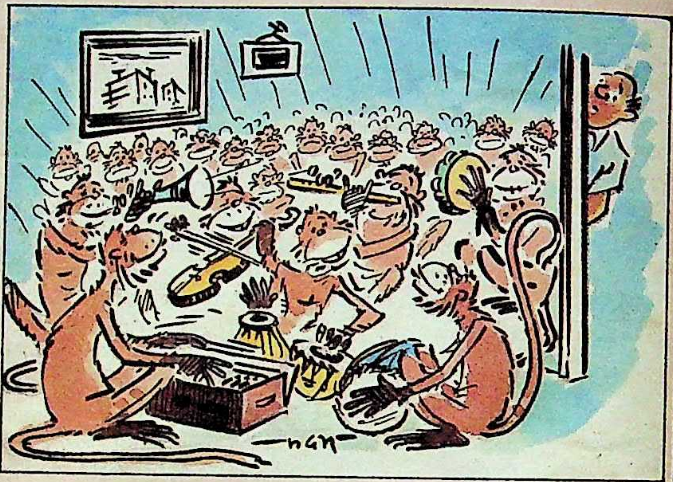

पहले मांगलिक अवसरों पर शहनाई-ताशे, ढोल मजीरे और बैंडबाजों का जो स्थान था, वही अब आरकेस्ट्रा ने ले रखा है। किसी शादी-विवाह में चले जाइए, किसी की वर्षगांठ पर चले जाइए संगीत की सुरलहरियों में आप खो जायेंगे। लेकिन बिना किसी प्रयोजन के किसी स्कूल के बंद कमरे से संगीत की गंगा बहने लगे और कोई आदमीजात तक दिखायी न दे, तो आश्चर्य तो होगा ही। लेकिन असम में तेजपुर के एक केंद्रीय विद्यालय के संगीत-विभाग से छुट्टी के दिन यानी इतवार को जब आरकेस्ट्रा की धुनें सुनायी पड़ने लगीं, तो स्कूल का चौकीदार सकते में आ गया। उसने जब दरवाजा खोला, तो देखता क्या है कि कमरे में तकरीबन दो सौ बंदर जमा हैं। उनमें से कुछेक वाद्ययंत्रों पर हैं, तो कुछेक रससिक्त श्रोता के रूप में झूम-झूम कर संगीत-संध्या का आनंद उठा रहे हैं।

तलाक के चलते

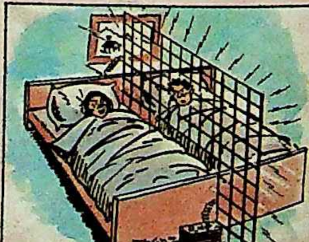

शादी करना जितना आसान है, तलाक लेना या देना उससे भी कठिन। फिर पश्चिम जर्मनी में तो तलाक के कानून इतने कड़े हैं कि यदि कोई दंपति आपस में तलाक चाहता है, तो पति-पत्नी को एक वर्ष पूर्व से ही अलग-अलग रहना पड़ता है। लेकिन किसी दंपति के सिर पर कानून का ऐसा हौवा सवार हो जाये कि अलग-अलग रहने के लिए वे अपने बिस्तर पर बिजली का तार लगवा लें, तो आश्चर्य होता है। कानून की जद में आये एक दंपति को जब कोर्ट ने अलग-अलग रहने का आदेश दिया, तो वे बड़े संकट में फंस गये, क्योंकि उनके पास छोटा-सा एक ही कमरा था और उसमें भी एक ही बेड। जब उन्होंने देखा कि वे कोर्ट की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपने बिस्तर को दो भागों में बांट दिया और बीच में बिजली का तार दौड़ा दिया, ताकि चाहे-अनचाहे दोनों कभी हमबिस्तर न हो सकें। इस प्रकार दोनों सालभर एक-दूसरे से अलग-अलग रहने में सफल हुए और कोर्ट ने तलाक स्वीकृत कर दिया।

—डा० मुश्ताक अली

महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी

एक और लाटरी विवाद

चार साल पहले पूरे देश के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में बननेवाले शहीद स्मारक के लिए आयोजित ५ करोड़ रुपए की इनाम राशिवाली महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी के टिकट यह मानकर खरीदे थे कि यह सरकारी लाटरी है। इसका कारण यह था कि इन टिकटों पर राजीव गांधी और अर्जुन सिंह के चित्र थे। यह प्रचार भी किया गया था कि इसे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन इस लाटरी के कितने टिकट बिके व किनको इनाम मिला, इसका किसी को पता नहीं चला। अब खुद शंकराचार्य के कहने पर इस लाटरी के खिलाफ जबलपुर उच्चन्यायालय में मुकदमा दायर हुआ है तथा अनेक स्वतंत्रता संग्राम-सेनानी कह रहे हैं कि इस लाटरी से उनका कोई लेना-देना नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? इसका फैसला तो न्यायालय करेगा, लेकिन 'माया' ने इस विवाद की अपनी ओर से गहरी छानबीन की है। प्रस्तुत है, रपट:

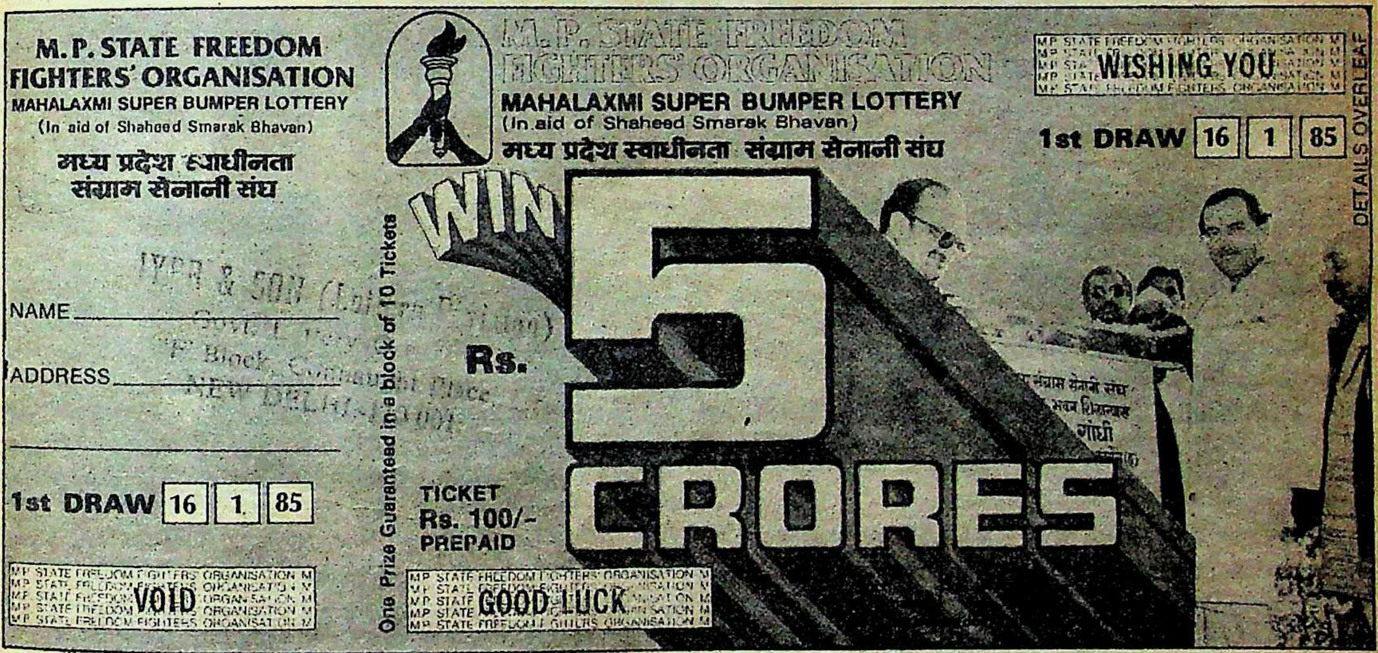

M. P. STATE FREEDOM FIGHTERS' ORGANISATION
MAHALAXMI SUPER BUMPER LOTTERY
(In aid of Shaheed Smarak Bhavan)
मध्य प्रदेश स्वाधीनता संग्राम सैनानी संघ
NAME
ADDRESS
1st DRAW 16 1 85
VOID

M.P. STATE FREEDOM FIGHTERS' ORGANISATION
MAHALAXMI SUPER BUMPER LOTTERY
(In aid of Shaheed Smarak Bhavan)
मध्य प्रदेश स्वाधीनता संग्राम सैनानी संघ
WISHING YOU
1st DRAW 16 1 85
WIN Rs. 5 CRORES
TICKET Rs. 100/- PREPAID
One Prize Guaranteed in a block of 10 Tickets
GOOD LUCK
DETAILS OVERLEAF

सरकारी लाटरी होने का भ्रम: राजीव गांधी और अर्जुन सिंह के चित्र से युक्त महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी का एक टिकट

मध्यप्रदेश में लाटरियों के साथ घोटाले कुछ इस तरह चस्पां रहे हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आने लगे हैं। शायद ही कोई ऐसी लाटरी होगी जो अनुमति, टिकटों की बिक्री, ड्रा, पुरस्कार-वितरण या औपचारिकताओं के निर्वाह आदि को लेकर कहीं-न-कहीं शिकायतों व विवादों के जटिल जाल में न उलझी हो। इस दशक के प्रारंभ से मप्र सरकार सरकारी लाटरियों के बजाय निजी लाटरियों पर मेहरबान रही। लिहाजा, निजी लाटरियों का धंधा खूब फलाफूला और जिस किसी को ऐसा कोई उपक्रम सूझा, उसने आव देखा न ताव, फटाफट सरकार के दरबार में लाटरी निकालने के लिए अर्जी लगा दी।

मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक संगठन है—'मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ'। नाम से जाहिर है कि यह आजादी के उन दीवानों का संगठन है जो १९४७ के पहले दासता से मुक्ति के लिए जेल गये, जिन्होंने अनगिनत कष्ट सहे और त्याग व बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत किये। करीब पांच साल पहले इन सेनानियों ने तय किया कि निधि एकत्र करने के लिए एक लाटरी निकाली जाये।

यह निश्चय करने के बाद संघ के महामंत्री कुंजबिहारी पाठक ने अपने हस्ताक्षर से तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को एक आवेदन दिया, जिसमें विषय के समक्ष 'सार्वजनिक कल्याण हेतु (शहीद स्मारक निर्माणार्थ) लाटरी/रैफल/उपक्रम हेतु निःशुल्क अनुमति की याचना' लिखा हुआ था। पत्र के पहले ही पैरे में अखिल भारतीय कांग्रेस-इ कमेटी के तत्कालीन महामंत्री राजीव गांधी द्वारा आठ माह पूर्व भोपाल में किये गये शहीद स्मारक भवन के शिलान्यास का हवाला देते हुए लिखा था कि निधि का अभाव स्मारक के निर्माण में बुनियादी बाधा सिद्ध हो रहा है और धनीमानी लोगों से ऐसे उपक्रमों के लिए दान-प्राप्ति उस तबके के लिए मृगमरीचिका है जो उन्हें उपकृत व लाभान्वित नहीं कर सकता। चुरहट चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी और आल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स समिति के लाटरी उपक्रमों व उन्हें प्रदत्त अनुमति व छूट का उल्लेख करते हुए इस आवेदन में पाठक ने लिखा, "अस्तु अत्यंत ही विनम्र और सम्मानपूर्वक याचना है कि मप्र स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संघ लाटरी/ रैफल जारी करने की अनुमति अपेक्षित सुविधाओं व छूटों के साथ देने की अनुकंपा करें।"

पाठक ने यह अर्जी तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को २० जून, १९८४ को दी और उन्होंने अगले ही दिन इस अर्जी पर वित्तमंत्री के नाम स्पष्ट लिखा, "कृपया अनुमति दें।" झुमुकलाल भेंडिया उस समय वित्तमंत्री थे। मुख्यमंत्री के इतने स्पष्ट आदेश की अवहेलना करना या उसे लटकाये रखना किसी भी वित्तमंत्री के बूते की बात नहीं है। भेंडिया

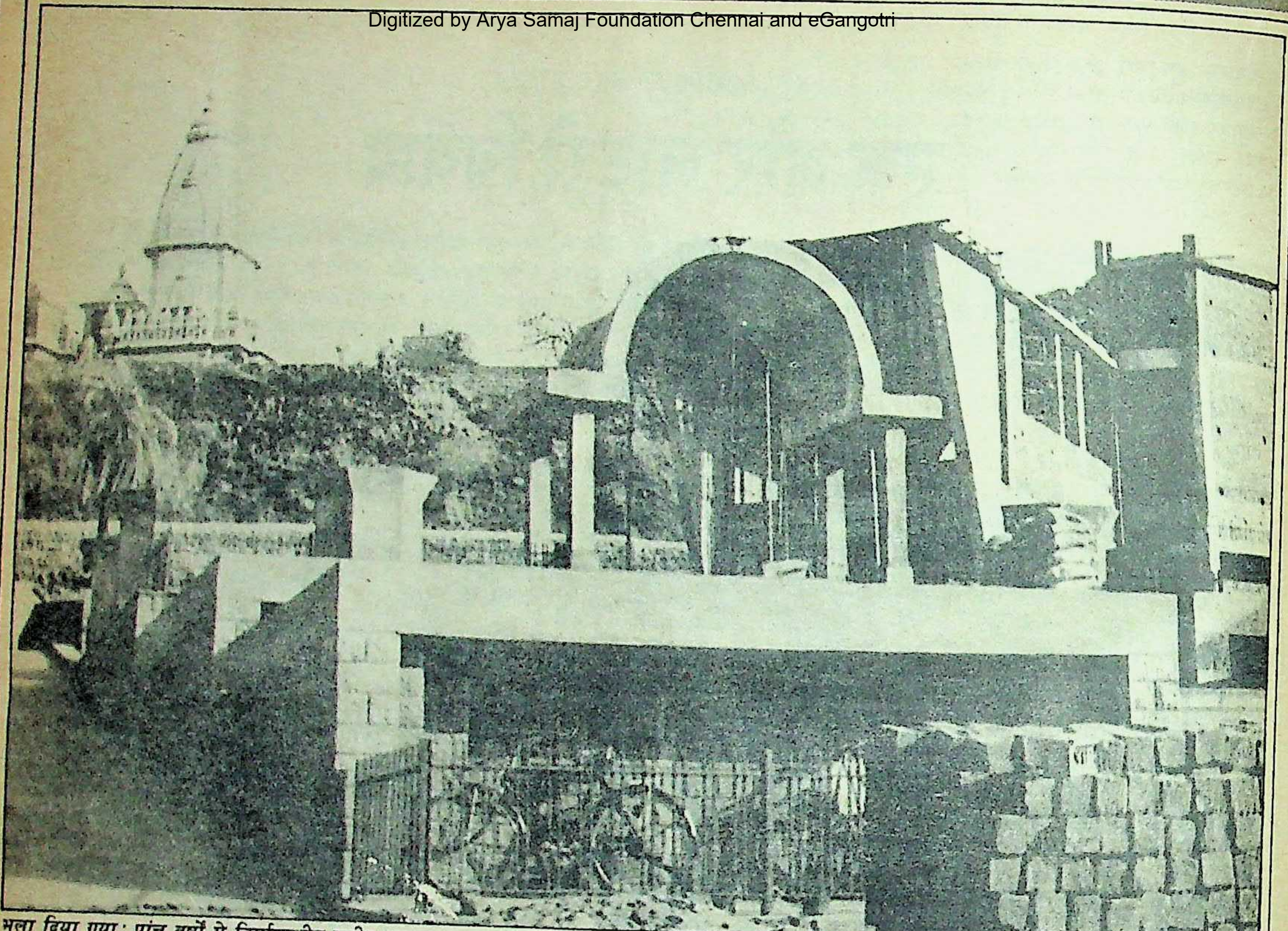

भुला दिया गया : पांच वर्षों से निर्माणाधीन शहीद स्मारक

ने २३ जून को अपनी अभिस्वीकृति प्रदान कर दी। २० जुलाई को पाठक वित्तसचिव से वल्लभ भवन में मिले और २७ जुलाई को उन्होंने वित्तसचिव को पुन: पत्र लिखा और अनुमति शीघ्र देने की याचना की। महामंत्री महोदय ने अपने इस पत्र में लिखा कि यों तो केंद्र व राज्य सरकारों की राष्ट्रीय नीति के अनुसार वह औरों की अपेक्षा अधिक छूट के पात्र हैं, तथापि वह उससे अधिक छूट की याचना नहीं कर रहे हैं जो मप्र शासन ने चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी और तदुपरांत रेडक्रास सोसायटी, भोपाल को दी है।

अनुमति : महामंत्री के इस पत्र का वांछित प्रभाव पड़ा और तीसरे ही दिन ३० जुलाई, १९८४ को मप्र शासन के अवरसचिव वित्त एसपी अग्रवाल ने पाठक को पत्र लिखा कि शहीद स्मारक निर्माणार्थ लाटरी/ रैफल उपक्रम हेतु आपको केवल एक ड्रा अन्य औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने की प्रत्याशा में आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अवरसचिव ने पत्र क्रमांक-१५०९/३८१६/८४/नि-३/चार में आगे लिखा कि आप यह बताने का कष्ट करें कि यह एक ड्रा आप कितनी राशि का निकालेंगे और आपकी तत्संबंधित विस्तृत योजना क्या होगी? इसके जवाब में पाठक ने लिखा कि चूंकि, शासन नें छह ड्रा के स्थान पर एक ही ड्रा की अनुमति दी है, अत: संघ अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वित्तसचिव शिवरामन महानुभाव द्वारा २०-७-८४ को भेंटवार्ता में प्रदत्त परामर्श के अनुसार एकमेव बम्पर ड्रा का उपक्रम करने को बाध्य हैं।

भोपाल में शहीद स्मारक कब बनकर तैयार होगा, दावे से कोई नहीं कह सकता? कायदे से शहीद स्मारक को पांच साल पहले बन जाना चाहिए था, किंतु वह अभी तक अधूरा है। स्मारक कब बनेगा और फैसला कब आयेगा, इसका सभी को इंतजार है।

उल्लेखनीय है कि दिये गये आवेदनों में पाठक ने यह बात कहीं भी नहीं कही है कि छह ड्रा की अनुमित देने में असमर्थता की स्थिति में उन्हें बंपर ड्रा की अनुमति दी जाये या छह ड्रा की मंजूरी न मिलने पर वे बंपर ड्रा निकालने को बाध्य होंगे। स्पष्ट है कि उनका पहला प्रयास अनुमति हासिल करना था। भले ही इसमें उन्हें चुरहट और रेडक्रास लाटरियों को ढाल और मुद्दा क्यों न बनाना पड़ा हो? आगे अपने बंपर ड्रा का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने वित्तसचिव के उक्त मौखिक परामर्श का हवाला दिया। यदि यह बात सही है, तो वित्तसचिव की भूमिका एक बार फिर संदेह की बलि चढ़ जाती है और यदि यह बात कपोलकल्पित है, तो प्रेरणाप्रद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्माननीय संगठन का एक जिम्मेदार महामंत्री 'चतुर' साबित होता है।

बंपर ड्रा : बहरहाल, संघ ने पांच करोड़ रुपए का रैफल ड्रा निकालने का फैसला किया, जिसके लिए प्रति टिकट एक सौ रुपए मूल्य की दस लाख टिकटें पांच सीरीजों में जारी करने का फैसला किया गया। तय हुआ कि इनाम की राशि टिकटों की राशि

का पचास प्रतिशत हो। महामंत्री महोदय ने वित्तसचिव को जो प्रस्तावना भेजी, तदनुसार पांच करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का समायोजन इस प्रकार करना तय हुआ कि सभी सीरीजों से इनामी ड्रा निकाले जायें, किंतु कोई भी सिंगल इनाम पंद्रह लाख रुपए से अधिक न हो।

संघ का अनुमान था कि इस उपक्रम से उसे बतौर रायल्टी पंद्रह प्रतिशत अर्थात ७५ लाख रुपए की रकम प्राप्त होगी, जिसे अंततोगत्वा शहीद स्मारक न्यास को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। न्यास में अर्जुन सिंह (अध्यक्ष), झुमुकलाल भेंडिया, मगनलाल बागड़ी, पं० कुंजबिहारी पाठक (प्रबंध न्यासी)· एवं इन चारों द्वारा चयनित कतिपय विभूतियों के समावेश का प्रावधान रखा गया। संघ ने यह घोषणा की कि रैफल का ड्रा संघ के पंजीकृत मुख्यालय जबलपुर में वित्तमंत्रालय के प्रतिनिधि के प्रत्यक्ष निर्देशन में निकाला जायेगा।

शहीद स्मारक के निर्माण के लिए प्रायोजित इस लाटरी का नामकरण 'महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी' किया गया और दिल्ली स्थित मैसर्स अय्यर ऐंड संस को इसका सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त किया गया। तमाम अखबारों में विज्ञापन छपे। इसी मोड़ पर कुछ ऐसी बातें हुई, जिन्होंने महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी को विवादों में जकड़ दिया।

टिकट-बिक्री: महालक्ष्मी लाटरी मप्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के लिए मैसर्स अय्यर ऐंड संस की प्रायोजित लाटरी थी और संघ एक पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। लाटरी के जारी और बिके टिकटों को देखें, तो 'एम पी स्टेट' शब्द के उपयोग से भ्रम उपजता है कि मप्र शासन इससे जुड़ा हुआ है। यह भ्रांति और घनी तब हो जाती है, जब हम पाते हैं कि हरेक टिकट में राजीव गांधी और अर्जुन सिंह का चित्र छपा हुआ है। यह चित्र भोपाल में शहीद स्मारक के शिलान्यास-प्रसंग का है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने सामान्जन को टिकट खरीदने के लिए ललचाया व प्रेरित किया होगा।

इसी क्रम में जगद्गुरु शंकराचार्य का उल्लेख भी आवश्यक है। इस संदर्भ में एक याचिका भी मप्र हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी, जिस पर अदालत ने अंतरिम स्थगन भी जारी किया था। जबलपुरवासी प्रतीश पांडे ने अपनी याचिका में इस बात पर आपत्ति की थी कि लाटरी के टिकटों में शंकराचार्य के चित्रों का उपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सीपी सेन और एस अवस्थी ने ५ फरवरी, १९८५ को यह याचिका निरस्त कर दी। 'माया' ने जब सतीश पांडे से संपर्क किया, तो वे शंकराचार्य का चित्रयुक्त टिकट प्रस्तुत करने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो टिकट खरीदा था उसमें शंकराचार्य का चित्र था, लेकिन वह गुम हो गया है। जांच-पड़ताल के दौरान 'माया' ने पाया कि टिकट पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के चित्र की बात सही नहीं है। हां, यह सही है कि शंकराचार्य ने इस उपक्रम को अपना आशीर्वाद दिया और समाचार-

साक्षात्कार: कुंजबिहारी पाठक

"लाटरी निजी कहां थी?"

"मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः मैं कुछ नहीं कहूंगा," मुलाकात होने पर मध्यप्रदेश स्वाधीनता संग्राम सेनानी संघ के महामंत्री कुंजबिहारी पाठक ने छूटते ही कहा, किंतु जब उनके समक्ष जनसामान्य के सम्मुख वस्तुस्थिति उजागर करने के 'माया' के प्रयोजन का उल्लेख किया गया, तो वे औपचारिक वार्तालाप के लिए तैयार हो गये। प्रस्तुत हैं, उनसे हुई बातचीत के महत्वपूर्ण अंश:

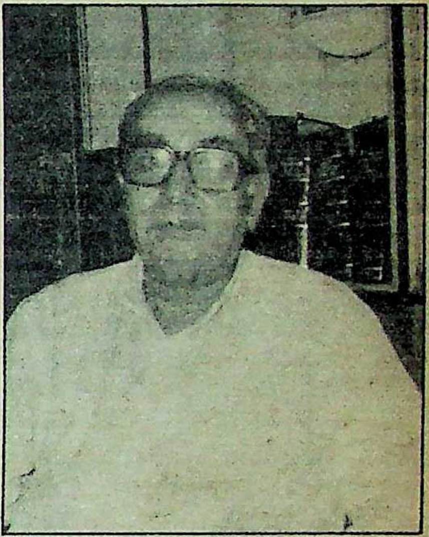

माया: *क्या मप्र स्वाधीनता संग्राम सेनानी संघ पंजीबद्ध संस्था है?*

पाठक: अवश्य पंजीबद्ध है।

माया: *संस्था के कितने सदस्य हैं?*

पाठक: यह तो ध्यान नहीं है। मैं उसमें महामंत्री हूं और मगनलाल बागड़ी अध्यक्ष थे।

माया: *शहीद स्मारक के निर्माण के लिए लाटरी जारी करने का फैसला कब हुआ?*

पाठक: इसका मुझे ध्यान नहीं है। जहां तक मुझे खयाल आता है, सन १९८४ के प्रारंभ में इस आशय का फैसला हुआ था।

माया: *क्या शासन ने संघ को लाटरी निकालने की औपचारिक अनुमति दी थी?*

पाठक: बिना अनुमति के लाटरी भला कैसे निकालेंगें? अनुमति की कापी कोर्ट में भी पेश की गयी है।

माया: *क्या यह सही है कि लाटरी का टिकट एक सौ रुपए मूल्य का था और पांच करोड़ रुपए के पुरस्कारों की घोषणा की गयी थी?*

पाठक: टिकट का मूल्य सौ रुपए था और पुरस्कारों की घोषणा भी की गयी थी, लेकिन लोगों ने करने कहां दिया?

माया: *क्या अय्यर ऐंड संस आपके सोल बिक्री एजेंट थे?*

पाठक: एजेंट क्या वे तो पूरे-पूरे मालिक ही थे।

माया: *आरोप है कि आपने शासन को पुरस्कारों का विवरण नहीं दिया...*

पाठक: यह तो न्यायालय ही बतायेगा। न्यायालय में विवरण पेश किया जा चुका है। अदालत के पास पूरा ब्योरा है।

माया: *निजी लाटरी में 'एम पी स्टेट' शब्द का उपयोग करना क्या अनुचित नहीं है?*

पाठक: भाई मेरे, लाटरी निजी कहां थी? वह तो शासन की अनुमति से थी और उसी की थी। भला मैं बीच में कहां से आ गया?

माया: *प्रतीश पांडे और रामनाथ मसुरह्या नामक दो व्यक्तियों ने कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। एक याचिका में दलील दी गयी थी कि लाटरी के टिकट पर जगत्गुरु शंकराचार्य का चित्र है, अतः उसे बंद किया जाये...*

पाठक: यह सरासर गलत है। टिकट में उनकी फोटो नहीं है। पेपरों में इश्तेहार जरूर दिया गया था। इसके लिए उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था। जबलपुर में एक पार्वती पांडे हैं जो शंकराचार्य की खास भक्त मानी जाती हैं। शंकराचार्य जबलपुर में उसी के यहां ठहरते हैं। इन्हीं पार्वती पांडे ने पैसा न मिलने पर जबर्दस्ती अपने लड़के प्रतीश पांडे से याचिका दायर करवा दी।

माया: *क्या यह सही है कि कोर्ट ने लाटरी के ड्रा को अवैधानिक घोषित कर दिया था?*

पाठक: अभी तो कोर्ट का निर्णय ही नहीं हुआ है। फिर लाटरी ड्रा को अवैधानिक घोषित करने का सवाल ही कहां उठता है?

माया: *शहीद स्मारक के निर्माण की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?*

पाठक: मैंने तो उससे जो पैसा प्राप्त हुआ था, उसे मुख्यमंत्री के सुपुर्द कर दिया था। अब वे जानें। परंतु जब भोपाल जाता हूं, तो निर्माण में प्रगति दिखती है।

माया: *आपने मुख्यमंत्री को कितना पैसा दिया था?*

पाठक: ग्यारह लाख सत्ताइस हजार नौ सौ रुपए।

—एसपी त्रिपाठी

पत्रों में उनके चित्रों के जरिये लाटरी का प्रचार किया गया था। १५ नवंबर, १९८४ को शंकराचार्य ने अपने आशीर्वचन में कहा, "मध्यप्रदेश स्वाधीनता संग्राम सैनिक द्वारा प्रस्तावित शहीद स्मारक भारतीय अध्यात्म दर्शन-इतिहास का शोध संस्थान होगा। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोद्देश्य इस उपक्रम की सफलता की कामना करते हैं।"

विवादास्पद ड्रा: अंततोगत्वा १२ मार्च, १९८५ को जबलपुर में अशोका होटल में महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी का ड्रा निकाला गया। अय्यर ऐंड संस के प्रतिनिधि सबरवाल, दिल्ली के अधिवक्ता चरणदास साहू तथा कुछ अन्य लोगों की उपस्थिति में ड्रा निकाला गया। निर्णायक मंडल के सदस्य थे: बलभद्र प्रसाद तिवारी, केके कुलकर्णी, बीआर दामले, राजनलाल सोनकर, जीएस मिश्रा, यूसुफ और टीआर शरीफ। बलभद्र प्रसाद तिवारी उस दिन निर्णायक थे, किंतु आज वे ड्रा को धोखाधड़ी करार देते हैं। वे राजधानी से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र के संपादक-प्रकाशक भी हैं। उन्होंने 'माया' से चर्चा में कहा कि जब ड्रा निकला, तो गिने-चुने लोग मौजूद थे और उनमें होटल के बेयरे तक शामिल थे। जब उन्होंने आपत्ति की, तो एजेंट सबरवाल ने उसका प्रतिवाद किया।

अब विरोध क्यों: स्वरूपानंदजी द्वारा लाटरी का प्रचार

बहरहाल, ऐसे माहौल में ड्रा निकला और जल्द ही एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामनाथ मसुरहा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। मसुरहा ने मांग की कि लाटरी पर रोक लगायी जाये। चूंकि एक ड्रा हो चुका था, अतः मांग की गयी कि पुरस्कार वितरण रोक दिया जाये। मजेदार बात यह है कि छपे और बिके टिकटों की संख्या, ड्राओं की संख्या, पुरस्कार की राशि, विजेताओं के नाम आदि का विवरण संचालनालय, अल्प बचत एवं लाटरी के भी पास उपलब्ध नहीं है। शंकाओं व रहस्य का दायरा तब और बढ़ा, जब सोल सेलिंग एजेंट के भागीदार सबरवाल महाशय विदेश पलायन कर गये।

मप्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ और उसके इस उपक्रम पर इस बीच एक और उंगली उठी। जबलपुर नगर स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संघ ने एक बयान जारी कर कहा कि इस संघ का लाटरी से कोई लेनादेना नहीं है। अध्यक्ष मुलायम चंद्र जैन व मंत्री शंकरलाल शुक्ल ने कहा कि वरिष्ठ सदस्य सवाईमल जैन व साथियों ने इस लाटरी का मर्वदा विरोध किया है।

इस लाटरी-गाथा का अंतिम किंतु असमाप्त अध्याय यह है कि मसुरहा की याचिका जबलपुर उच्चन्यायालय में लंबित है। कुंजबिहारी पाठक इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या घोटाले से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि संबंधित सारा ब्योरा अदालत के पास है। न्यायालय के फैसले का दोनों ही पक्षों-पाठक और मसुरहा को इतजार है। मसुरहा ने मामले की पैरवी के लिए जबलपुर के नामीगिरामी वकील को तय किया है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है। उनका कहना है कि जगद्गुरु शंकराचार्य के शिष्य होने के नाते वकील साहब उनसे फीस नही ले रहे हैं। अदालत के फैसले से दूध-का-दूध, पानी-का-पानी होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन फैसले में अभी कितनी देर लगेगी, कहा नहीं जा सकता? इसी प्रकार भोपाल में शहीद स्मारक कब बनकर तैयार होगा, दावे से कोई नहीं कह सकता? संघ के महामंत्री मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को लाटरी से अर्जित ११ लाख रुपए की राशि सौंप चुके हैं। कायदे से शहीद स्मारक को पांच साल पहले बन जाना चाहिए था, किंतु वह अभी तक अधूरा है। स्मारक कब बनेगा और फैसला कब आयेगा, इसका सभी को इंतजार है।

—सुधीर सक्सेना, जबलपुर से एसपी त्रिपाठी के साथ

> **इस लाटरी-गाथा का अंतिम किंतु असमाप्त अध्याय यह है कि मसुरहा की याचिका जबलपुर उच्चन्यायालय में लंबित है। कुंजबिहारी पाठक इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या घोटाले से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि संबंधित सारा ब्योरा अदालत के पास है।**

महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी

कुछ और तथ्य

लाटरी के खिलाफ याचिका दाखिल करनेवाले रामनाथ मसुरहा का कहना है कि उन्होंने लाटरी के विरुद्ध याचिका स्वामीजी (स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती) के कहने पर दायर की है। स्वामीजी ने उनसे कहा था कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अतः आप याचिका दायर करें, तो उस पर जरूर विचार होगा।

● मैसर्स अय्यर ऐंड संस के भागीदार सबरवाल इन दिनों कहां है, पता नहीं? अय्यर ऐंड संस इंदौर की विवादास्पद टेबुल टेनिस लाटरी के भी सोल सेलिंग एजेंट थे।

● मप्र राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के अध्यक्ष बागड़ी का स्वर्गवास हो चुका है और फिलहाल कुंजबिहारी पाठक ही इसके कर्ताधर्ता हैं।

● स्वरूपानंदजी के कतिपय भक्तों का कहना है कि पूज्य शंकराचार्यजी ने महालक्ष्मी सुपर बंपर लाटरी को आशीर्वाद इसलिए दिया, क्योंकि वे स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं।

● बलभद्र प्रसाद तिवारी आज लाटरी के मुखर विरोधी हैं, किंतु लाटरी, जिसके वे निर्णायक भी थे, का रिजल्ट उन्हीं के साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हुआ है। वे अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला।

● कुंजबिहारी पाठक टिकट पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र को अनुचित व आपत्तिजनक नहीं मानते। उनका तर्क है कि चुरहट चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसायटी के टिकट पर मदर टेरेसा की फोटो छपी थी, लेकिन किसी ने उस पर उंगली नहीं उठायी।

● मसुरहा की याचिका पर हाईकोर्ट ने १५ दिसंबर, १९८६ को आदेश दिया था कि संघ के महामंत्री पाठक मय ब्यौरे के कोर्ट में उपस्थित हों।

● स्वरूपानंदजी की शिष्या कल्याणी पांडे टिकट के साथ शंकराचार्य की फोटो और आशीर्वचन पर उनके हस्ताक्षर को गलत बताती हैं और कहती हैं कि यह जालसाजी है। कल्याणी पांडे दहेज विरोधी प्रकोष्ठ की प्रांतीय संयोजिका हैं। इसके विपरीत पाठक कहते हैं कि शंकराचार्यजी ने दिल्ली में उनसे स्वयं शिकायत की थी कि उन्हें अभी तक उपरोक्त चित्र समाचारपत्रों में देखने को नहीं मिला।

■

पेश है जनाब एक स्वाद लाजवाब,
'रश्मि' ज़र्दे की विविधता में वही परम्परागत स्वाद,
वाह! क्या लाजबाब.......
रश्मि ज़र्दा
सत्यपाल शिवकुमार 355, नया बाँस, दिल्ली-110006
Rashmi
ZAFRANI PATTI
Rashmi
ZARDA
ZAFRANI PATTI
SCENTED CHEWING TOBACCO
SATYAPAL SHIVKUMAR
355, NAYA BANS, DELHI-110006 (INDIA)
BLISS/DEL

(वैधानिक चेतावनी – तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।)

जहां महिलाएं अद्भुत कुशलता प्राप्त करती हैं
सोवियत नारी
सोवियत नारी
सोवियत नारी

सोवियत नारी

सचित्र पारिवारिक मासिक

यही सही मायने में पूरे परिवार की पत्रिका है। इसमें बच्चों के पालन-पोषण, घर- गृहस्थी, परिवार के स्वास्थ्य, नवीनतम फैशन, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कसीदाकारी, पाक-विद्या और सारे संसार की नारियों की दिलचस्पी के अनेकानेक विषयों पर रोचक सामग्री व लेख छापे जाते हैं। 'सोवियत नारी' पत्रिका अंग्रेजी, हिंदी, बंगला समेत आठ भाषाओं में प्रकाशित होती है।

12 अंक मुफ्त

33% बचत कीजिए

"सोवियत नारी" के लिए डी डी/एम ओ प्रेषित है
तीन वर्ष का चन्दा 55 रुपये
एक वर्ष का चन्दा 28 रुपये
(अवांछनीय काट दीजिये)

नाम ____________________
पता ____________________

यह विज्ञापन और भुगतान निम्न पते पर भेजिये
इंटरकांटीनेंटल सर्विस एजेंसीज ब्यूरो
ए-7, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

MMK

पत्रिका के चंदे शीघ्र बढ़ जायेंगे
जल्दी कीजिए
विशेष छूट का लाभ उठाइये
तीन वर्ष के लिए चंदा भेजिए
और 33% की बचत कीजिए
12 अंक मुफ्त

पत्रिका की प्रति आप निम्न पते पर खरीद सकते हैं
यू.एस.एस.आर. बुक सेंटर
ए-7, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110 001

पटनायक और सत्पथी आमने-सामने

उड़ीसा में मुख्यमंत्री जानकीवल्लभ पटनायक और हाल ही कांग्रेस में दाखिल हुईं पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी की तकरार बढ़ती जा रही है। क्या यह लड़ाई चुनाव-वर्ष में उड़ीसा में कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगी? क्या नंदिनी सत्पथी विगत दस वर्षों से ऐतिहासिक रूप से अपनी गद्दी पर जमे मुख्यमंत्री पटनायक को चुनाव के पूर्व अपदस्थ करवाने में कामयाब हो सकेंगी?

वर्चस्व को चुनौती: (बायें से) उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांहूचरण लेंका, जानकीवल्लभ पटनायक और श्रीमती जयंती पटनायक

कहानी २२ साल पुरानी है। उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी 'जनकांग्रेस' के टिकट पर कटक जिले के धर्मशाला विधानसभाई क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी जमानत गंवाने के बाद मायूस व हतोत्साहित जानकीवल्लभ पटनायक कटक के ओल्ड कालेज लेन स्थित अपने किराये के मकान में गर्दिश के दिन गुजार रहे थे। पटनायक के वे दिन बहुत प्रतिकूल थे, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके जिन हरेकृष्ण महताब ने पटनायक को राजनीति करने के लिए अपनी हथेली दी थी, उन्होंने भी उस समय अपनी हथेली उनसे खींच ली थी। इतना ही नहीं, महताब ने अपने अखबार 'प्रजातंत्र' के संपादक-पद से भी पटनायक की छुट्टी कर दी थी। लिहाजा, चारों तरफ परिस्थिति विपरीत देखकर जानकीवल्लभ फिर कटक लौटकर अपने साहित्यिक मासिक 'पौरुष' के प्रकाशन में जुट गये थे।

आर्थिक तंगी की वजह से इस मासिक पत्र के प्रकाशन में भी उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इस तरह तीन-चार वर्ष निकल गये। १९७१ के मध्य तक पटनायक बहुत प्रयास करने के बावजूद भी राजनीति के हाशिये से निकल नहीं पाये थे। पर एक दिन अचानक नंदिनी सत्पथी का उन्हें संदेश मिला कि भुवनेश्वर आकर वे उनसे तत्काल संपर्क करें। वे संसदीय चुनाव हेतु टिकट वितरण की सरगर्मियों के दिन थे। नंदिनी सत्पथी से जब पटनायक की बात हुई, तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न था, क्योंकि नंदिनी ने उन्हें कटक संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिलाने का आश्वासन दिया था।

उन दिनों उड़ीसा में गैरकांग्रेसी सरकार की हुकूमत थी और कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। उस समय उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजमोहन मोहंती थे, पर उड़ीसा कांग्रेस की राजनीति का सारा दारोमदार नंदिनी सत्पथी पर ही था। श्रीमती गांधी के वे सीधे संपर्क में थीं। बहरहाल, नंदिनी सत्पथी के अनुग्रह से कटक संसदीय सीट से कांग्रेस टिकट पर जानकीवल्लभ पटनायक चुनाव जीत गये। फिर वह दिन और आज का यह दिन, पटनायक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

पर इस कथा का असली सार-तत्व तो आगे है। १९७२ के जून माह में जब विश्वनाथ दास की सरकार गिर गयी, तो उड़ीसा की सत्ता में काबिज होने का अवसर कांग्रेस को मिला। नंदिनी सत्पथी को कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी। १९७३ में जब २५ कांग्रेसी विधायक 'प्रगति पार्टी' में टूटकर चले गये, तो नंदिनी सत्पथी की सरकार गिर गयी। फिर भी इस समय तक उड़ीसा की कांग्रेस-राजनीति में नंदिनी का ही 'वन वुमन

शो' था, क्योंकि उड़ीसा के कांग्रेस-अध्यक्ष पद से १९७२ में ब्रजमोहन मोहंती को हटाकर अध्यक्ष पद भी नंदिनी के जिम्मे ही कर दिया गया था। सांसद के रूप में जानकीवल्लभ पटनायक की अपने प्रति निष्ठा से प्रसन्न होकर नंदिनी ने पटनायक के लिए दिल्ली में जबर्दस्त लाबींग की और पटनायक केंद्रीय उपमंत्री की कुरसी पाने में कामयाब हो गये।

वे दिन उड़ीसा में कांग्रेस के संघर्ष के दिन थे। पर १९७४ में जब यहां मध्यावधि चुनाव हुआ, तो नंदिनी ने एड़ी-चोटी एक कर कांग्रेस के लिए विधानसभा में पर्याप्त सीटें हासिल कर लीं और सात कम्युनिस्ट विधायकों का समर्थन लेकर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की खोयी हुई सत्ता को उडीसा में बहाल किया। बाद में नंदिनी के खासुलखास विधायक व राजनीतिक सहयोगी उनके खिलाफ हो गये और श्रीमती गांधी की भी भृकुटि उन पर टेढ़ी हो चुकी थी। यह कांग्रेस में संजय-युग का प्रारंभिक काल था। संजय नंदिनी को नापसंद करते थे, यह बात जब जानकीवल्लभ ने भांप ली, तो फौरन पाला बदल कर वे नंदिनी के विरोधी हो गये। नंदिनी विरोधी बन जाने के कारण संजय गांधी ने प्रसन्न होकर उन्हें १९७६ में केंद्रीय उपमंत्री से केंद्रीय राज्यमंत्री बनवा दिया। १९७६ के दिसंबर माह में नंदिनी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह विनायक आचार्य नये कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाये गये। फिर १९७७ में संजय ने ही पटनायक को उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस की कुरसी सिपुर्द करवा दी। १९७७ में नंदिनी कांग्रेस से अलग हो चुकी थीं और उड़ीसा में कांग्रेस की दुकानदारी महज छह वर्षों की अल्पावधि में ही पटनायक ने पूरे तौर पर हथिया ली। १९७७ के बाद से गुजरे ग्यारह वर्षों में अनगिनत बार नंदिनी सत्पथी ने दुबारा कांग्रेस में वापसी के लिए जब प्रयास किया, तो वे जानकीवल्लभ पटनायक ही थे, जिन्होंने हर बार नंदिनी के कांग्रेस प्रवेश पर ताला मार दिया। पर वही नंदिनी सत्पथी जब ४ अगस्त, १९८८ को कांग्रेस में आने में कामयाब हो गयीं, तो पटनायक हतप्रभ रह गये और पिछले आठ-नौ महीनों से नंदिनी सत्पथी से उनकी जमकर ठनी हुई है। पटनायक आशंकित हैं कि जिस महिला ने आज से अट्ठारह साल पूर्व कटक के ओल्ड कालेज लेन स्थित किराये के घर से खींचकर उन्हें संसद में भेजकर राजनीति में सामर्थ्यवान बनाया था, वही महिला अब अपने वर्षों पुराने घायल गुस्से में उन्हें सामर्थ्यहीन बनाने के गुर कारगर ढंग से कहीं न आजमाने लगे। लिहाजा, घात-प्रतिघात का खेल जारी है और भुवनेश्वर के राजनीतिक गलियारों में निरंतर तुर्शी बढ़ती ही जा रही है। लगभग हर महीने नंदिनी पटनायक-विरोधी अभियान के तहत दिल्ली जाती हैं और पीछे से परेशान पटनायक उनके वार का प्रतिकार करने भागे हुए दिल्ली पहुंचते हैं। पिछले दिनों जब १ मई को नंदिनी दिल्ली गयीं, तो फौरन ३ मई को जानकीवल्लभ पीछे-पीछे दिल्ली जा धमके। भुवनेश्वर के एक पुराने राजनीतिक खिलाड़ी कहते भी हैं, "पटनायक का यह सिलसिला १९८२ से ही है। जब कभी नंदिनी दिल्ली गयीं, तो पीछे से पटनायक भी वहां पहुंचे। दरअसल, पटनायक को सदैव यह चिंता खाये जा रही थी कि कहीं नंदिनी कांग्रेस में प्रवेश की अपनी मुहिम में कारगर न हो जायें। आखिरकार पटनायक के गले पर नंदिनी की तलवार लटक ही गयी।"

दरअसल, पटनायक को सदैव यह चिंता खाये जा रही थी कि कहीं नंदिनी सत्पथी कांग्रेस में प्रवेश की अपनी मुहिम में कारगर न हो जायें। आखिरकार, पटनायक के गले पर नंदिनी की तलवार लटक ही गयी।

युद्ध शिखर पर: बहरहाल, राजनीति में एक-दूसरे के विरुद्ध इस तरह की दौड़-धूप तो लगी ही रहती है। पर विगत २६ मार्च की घटना के बाद से पटनायक व नंदिनी का युद्ध बिलकुल शिखर पर पहुंचा हुआ है। दरअसल, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित पंचायती राजप्रणाली पर २६ मार्च को भुवनेश्वर के कल्याण मंडप में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी, सरोज खापर्डे, कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद तथा कांग्रेस के संयुक्त सचिव जनार्दन द्विवेदी भुवनेश्वर पहुंचे हुए थे। हवाईअड्डे पर इन केंद्रीय नेताओं के उतरते ही अचानक स्थिति संगीन हो गयी, जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व नंदिनी-खेमे के समर्थक पटनायक के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। हवाईअड्डे पर भगदड़ मच गयी। "पटनायक हटाओ, कांग्रेस बचाओ" के नारे ने पटनायक को बिलकुल हतप्रभ कर दिया था। पटनायक भांप गये कि आगे कल्याण मंडप की संगोष्ठी में भी यही नजारा होनेवाला है। लिहाजा, एहतियाती तौर पर उन्होंने केंद्रीय नेताओं को अपने दामाद सौम्यरंजन पटनायक के अग्रज निरंजन पटनायक (जो संप्रति उनकी सरकार में उद्योग व पर्यावरण विभाग के काबीना मंत्री हैं) के साथ घुमाने के बहाने कोणार्क भेज दिया। इधर पटनायक के अनुमान के मुताबिक कल्याण मंडप में सचमुच स्थिति विस्फोटक बनी हुई थी। वहां पटनायकविरोधी नारे लग रहे थे। इस हंगामे व अफरातफरी की स्थिति में उडीसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कान्हूचरण लेंका ने पूर्व मंत्री वसंत कुमार बिस्वाल से कहा कि वे उपद्रव को शांत करवायें। वसंत बिस्वाल लेंका के इस प्रस्ताव पर थोड़ा सुगबुगाये, पर नंदिनी के इशारे से वे रुक गये। लिहाजा, नंदिनी व लेंका में उस समय तेज झड़प हुई और लेंका ने नंदिनी से कहा, "आप वर्षों बाद कांग्रेस में आयी हैं, इसलिए आपको कांग्रेस को समझने में कुछ देर लगेगी।" यही कान्हूचरण लेंका १९७२ से १९७४ की अवधि में उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे, जिस अवधि में नंदिनी सत्पथी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी थीं। इतना ही नहीं, कान्हूचरण लेंका १९७४ में नंदिनी की सरकार में उद्योग राज्यमंत्री भी हुआ करते थे। पर आज हालात बदले हैं, तो सुर भी बदले हुए हैं।

बहरहाल, २९ मार्च को कल्याण मंडप की संगोष्ठी में स्थिति इतनी विस्फोटक हो गयी कि आखिरकार कान्हूचरण लेंका ने संगोष्ठी स्थगित कर दी। फिर उसी दिन दोपहर में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में बैठक शुरू हुई। इस बैठक के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को सूचना भी नहीं दी गयी थी। इस बैठक में नंदिनी सत्पथी व पूर्व मंत्री वसंत बिस्वाल को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव पर पटनायक सरकार के दो मंत्रियों-शरद पंडा तथा शेख मतलूब अली—को छोड़कर सभी ने दस्तखत किये। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हेमानंद बिस्वाल तथा सचिव विजय लक्ष्मी साहु को छोड़कर प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये। नंदिनी तथा वसंत बिस्वाल को पार्टी से निकालने का यह प्रस्ताव पुरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन दास तथा ढेंकानाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विधान मिश्र ने पेश किया था। नंदिनी सत्पथी ढेंकानाल से ही अभी विधायक हैं। यों जब इस प्रस्ताव के तुरंत बाद उड़िया समाचार पत्रों के पत्रकारों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लेंका से पूछा, तो उन्होंने ऐसे किसी भी प्रस्ताव की बात से इनकार किया था। पर लेंका 'माया' से कहते हैं, "यह प्रस्ताव लाया गया था। मंत्रियों, महत्वपूर्ण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने इस पर दस्तखत किये थे। प्रस्ताव लेकर सभी लोग मेरे पास इस अनुरोध के साथ आये थे कि मैं इसे आलाकमान तक भेज दूं। कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए मैंने उसे भेज दिया। नंदिनी सत्पथी को तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लाया गया था। पर उनकी ये गतिविधियां क्या कांग्रेस को मजबूत करेंगी?" कान्हूचरण लेंका के नंदिनी विरोधी तेवर को लेकर भुवनेश्वर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। क्या जानकीवल्लभ पटनायक अपने इस पुराने

कट्टर राजनीतिक दुश्मन को पटाने में कामयाब हो गये? ये और ऐसे ही अनेक सवाल राजनीतिक तीरंदाजों के मन में घुमड़ रहे हैं। आखिर पटनायक व लेंका के इस नये समीकरण का सबब क्या है? ५ मार्च, १९८८ को नित्यानंद मिश्र को हटाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाये गये लेंका वर्षों से पटनायक विरोधी के रूप में ख्यात रहे हैं। १९८० में लेंका जानकीवल्लभ पटनायक-मंत्रिमंडल में राजस्व व आवकारी विभाग के काबीना मंत्री थे। पर १९८१ में लेंका ने पटनायक के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए मंत्री-पद से इस्तीफा दे दिया था। लेंका के इस हमले से पटनायक उस समय बेहद तिलमिलाये थे। इसका बदला पटनायक ने लेंका से आखिरकार १९८४ में ले ही लिया और विधानसभाई चुनाव में लेंका का टिकट कटवा दिया। १९७१ के दिनों में लेंका उड़ीसा की राजनीति में तब खासे चर्चित हुए थे, जब महज २८ वर्ष की उम्र में उन्होंने चौद्वार विधानसभाई सीट से बीजू पटनायक जैसे दिग्गज को पराजित कर दिया था। बहरहाल, विधानसभाई चुनाव में टिकट कटने के बाद लेंका पटनायक के प्रति और उग्र हो उठे। लिहाजा, दिल्ली की सेवा करनी उन्होंने शुरू कर दी। फिर १९८७ में राजीव गांधी ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 'राष्ट्रीय सूखा समिति' का सदस्य बनाया। यह समिति भले ही उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, पर प्रधानमंत्री की निगाह में लेंका हैं, यह तो साबित हो ही गया। आखिरकार, उडीसा के कटक सदर क्षेत्र के खंडायत खत्री जाति के इस दिग्गज नेता को राजीव गांधी ने जब ५ मार्च, १९८८ को उडीसा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और ठीक उसके अगले माह राज्यसभा की सदस्यता भी दिलवा दी, तो जानकीवल्लभ पटनायक की बेचैनी बढ़ गयी। उड़ीसा में खंडायत जाति की सर्वाधिक आबादी है और राजनीतिक रूप से भी खंडायत कम जागरूक नहीं हैं। इस तरह लेंका को संगठन की कमान सौंप कर कांग्रेस आलाकमान ने पटनायक की पेंच तो कस ही दी थी, पर इसके ठीक पांच महीने बाद जब नंदिनी सत्पथी को भी बगैर पटनायक की राय व जानकारी के कांग्रेस में ले लिया गया, तो पटनायक की घुटन और बढ़ गयी। प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही लेंका ने पटनायक पर प्रहार करने शुरू कर दिये। लेंका को महत्वपूर्ण पद मिलने व नंदिनी के कांग्रेस में आने से क्षुब्ध पटनायक पर तब और पलीता चढ़ गया, जब ऐन उसी समय उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल बीएन पांडेय ने नंदिनी और लेंका की तारीफ में बयान जारी करने शुरू कर दिये। राज्यपाल पांडेय ने कहा था, "नंदिनी सत्पथी जैसी नेता को फिर से कांग्रेस में लेकर कांग्रेस आलाकमान ने उड़ीसा में कांग्रेस को बचा लिया है।" पांडेय के इस बयान से पटनायक का पारा गर्म हुआ, तो ऊपर से फिर पांडेय ने लेंका की भी ताबड़तोड़ तारीफ कर डाली कि लेंका कांग्रेस की दुर्दशा ठीक करेंगे। पटनायक के लिए यह भी असहनीय था। पर पांडेय उन्हें संभवतः तिलमिलाने पर तुले थे, इसलिए अगली कड़ी में उन्होंने यह बयान भी ठोंक दिया कि उड़ीसा के आदिवासी नेता व केंद्रीय राज्यमंत्री गिरिधर गोमांगो की उड़ीसा के आदिवासी अंचल में अपार लोकप्रियता है। इसलिए प्रांतीय नेतृत्व को उनके प्रभाव से लाभान्वित होना चाहिए। बहरहाल, इन बयानों की वजह से पटनायक के साथ बढ़े तनावों के बाद राज्यपाल पांडेय तो त्यागपत्र देकर भुवनेश्वर से चले गये, पर उड़ीसा में बदली परिस्थिति का नया कांग्रेसी समीकरण वे स्पष्ट कर गये। मसलन, एक तरफ पटनायक, तो दूसरी तरफ नंदिनी, लेंका और गोमांगो।

नवंबर, १९८८ के प्रारंभिक दिनों में पटनायक ने गोमांगो को अपमानित भी किया था, जब तीन करोड़ की लागतवाली टेली कम्यूनिकेशन प्रशिक्षण परियोजना की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी जानी थी। इस कार्य से क्योंकि गोमांगो को श्रेय मिलता, इसलिए पटनायक बिदके हुए थे और गोमांगो पर इस कुतर्क के साथ दबाव डाल रहे थे कि वे इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें, क्योंकि जिस जमीन पर वे परियोजना की बात सोच रहे हैं, उस जमीन पर पहले से एक परियोजना प्रस्तावित है। गोमांगो इससे काफी क्षुब्ध हुए थे। नतीजतन, पटनायक व गोमांगो के संबंध दिनोदिन बिगड़ते चले गये और बदले राजनीतिक परिवेश में स्वाभाविक रूप से गोमांगो और नंदिनी सत्पथी निकट आ गये। भीतरी जानकार बताते हैं कि जानकीवल्लभ दिल्ली में कौन-सी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं, इसके बारे में एक-एक सैकेंड की जानकारी गोमांगो भुवनेश्वर में फोन पर नंदिनी सत्पथी को दिया करते हैं और फिर अगली रणनीति तय की जाती है। यों शुरू में लेंका ने तो खुलकर पटनायक पर हल्ला बोल रखा था, पर नंदिनी खेमे से जुड़कर नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से। इस वर्ष जनवरी माह में तो पटनायक व लेंका का महाभारत बिलकुल सतह पर दीखने लगा था। लेंका ने कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर पटनायक को सांसत में डाल दिया था। इस प्रस्ताव में इस बात की आलोचना की गयी थी कि मौजूदा उड़ीसा शासन हरिजन व आदिवासियों के वास्ते प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं को कारगर कर पाने में विफल हो रहा है। हरिजन-आदिवासियों के विकास हेतु आये रुपयों का दूसरे मदों में दुरुपयोग हो रहा है। नतीजतन, उड़ीसा के ये गरीब अपने हक से पूरी तरह वंचित हैं। लेंका के इस विस्फोटक प्रस्ताव का समर्थन नंदिनी सत्पथी तथा पूर्व मंत्री वसंत बिस्वाल ने भी खुल कर किया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में एक कार्यान्वियन कोषांग का गठन होना चाहिए जो हरिजन-आदिवासियों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वियन पर मुस्तैद रहे। इस तरह एक ओर लेंका ने जहां पटनायक पर धावा बोल रखा था, वहीं दूसरी ओर पटनायक की सांसद पत्नी जयंती पटनायक दिल्ली में इस आरोप के साथ लेंका की जड़ खोद रही थीं कि लेंका सांसदों, मंत्रियों तथा विधायकों की उपेक्षा कर मनमाने ढंग से विभिन्न कमेटियों में मनोनयन कर रहे हैं। दरअसल, जयंती पटनायक से लेंका का सीधा टकराव कटक जिले की राजनीति को लेकर हो रहा था। लेंका भी कटक के हैं और कटक सदर क्षेत्र से विधायक होते रहे हैं और जयंती पटनायक भी कटक से ही सांसद हैं। जयंती अपने जिन लोगों को कटक में संगठन में काबिज कराना चाहती थीं, लेंका उसके लिए तैयार नहीं थे। इस बीच कटक जिले के बाकी क्षेत्र के एक प्रमुख लेंका-समर्थक की हत्या हो गयी। एक कांग्रेसी विधायक जो अपना नाम नहीं प्रकाशित कराना चाहते, 'माया' से कहते हैं, "मुख्यमंत्री पटनायक की महिमा अपरंपार है। जिन दिनों लेंका कटक की राजनीति को लेकर उनकी पत्नी जयंती से युद्धरत थे, उन दिनों भी पटनायक अनगिनत कार्यक्रमों में अपने साथ लेंका को ले गये। इसलिए यों कह सकते हैं कि लड़ाई जयंती और लेंका के बीच थी और पटनायक तटस्थ थे। यही वजह हुई कि हाल के महीनों में पटनायक ने नंदिनी सत्पथी के विरुद्ध अपनी मुहिम में लेंका को भी आसानी से शरीक कर लिया।"

लेंका ने
पूर्वमंत्री वसंत बिस्वाल से
कहा कि वे उपद्रव शांत करवायें। वसंत
बिस्वाल लेंका के इस प्रस्ताव पर सुगबुगाए,
पर नंदिनी के इशारे से वे रुक गये।

आपसी कूटनीति: सचमुच, मार्च महीने में लेंका का झुकाव जब पटनायक की तरफ परिलक्षित हुआ, तो राजनीतिक पंडितों ने पटनायक की उस्तादी मान ली। पर मात्र दो महीनों के भीतर ही लेंका पर ऐसा कौन-सा जादू हो गया जो अचानक वे पटनायक की जड़ कुरेदते-कुरेदते पटनायक की जड़ों को सींचने लगे। क्या लेंका उन पुराने जख्मों को भूल गये? क्या पटनायक से ज्यादा खुंदक उन्हें नंदिनी

सत्पथी से है, जबकि नंदिनी के हाथों उनका अब तक कोई अहित नहीं हुआ। लेंका 'माया' से कहते हैं, "मैं कभी जानकीवल्लभ का विरोधी नहीं था, न हूं। हमारे पार्टी आलाकमान ने जो कार्य मुझे सौंपा है, मैं बस उसे पूरा करने में जुटा हूं।" पर लेंका के निकटवर्ती बताते हैं कि पटनायक को अचानक समर्थन दे देना लेंका की कूटनीति है। अगर वे पटनायक का विरोध करते हैं, तो पटनायक मजबूत होंगे और अगर वे पटनायक का समर्थन करने का दिखावा करते रहते हैं, तो पटनायक को कमजोर करने में उन्हें ज्यादा आसानी होगी। लेंका सुरंग के भीतर से पटनायक के विरुद्ध पलीता बिछा रहे हैं और ऊपर-ऊपर सद्भाव का दिखावा भी कर रहे हैं। इसलिए अकसर वे दिल्ली दरबार को पटनायक के विरुद्ध गोपनीय पत्र लिखते रहने से नहीं चूकते। पटनायक के विरुद्ध जिन दिनों असंतुष्ट गतिविधियां काफी तेज थीं, उसी समय से लेंका मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। पटनायक व सत्पथी की लड़ाई को लेंका भी अपनी तरफ से हवा देने की फिराक में हैं। एक कांग्रेसी विधायक चुटकी लेते हुए कहते हैं, "भई, हमलोग बिहार से सीखते हैं। कभी उड़ीसा बिहार का ही हिस्सा था। इसलिए बिहार हमारा बड़ा भाई है। लेंका तारिक अनवर की राजनीति से सीख लेकर कदम बढ़ा रहे हैं। वे आलाकमान के कठघरे में इस आरोप के साथ कतई खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हीं की वजह से पटनायक को परेशानी हो रही है।" लेंका के मित्र पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र रथ भी जब से कांग्रेस में आये हैं, तब से उन्होंने भी अपने रथ को पटनायक की तरफ मोड़ रखा है। जब यही रामचंद्र रथ संजय-युग के सितारे थे और केंद्रीय स्तर पर इनका जबर्दस्त रुतबा था, उन दिनों रथ पटनायक के प्रबल विरोधी हुआ करते थे। पर साढ़े चार वर्ष बाद कांग्रेस में आने के बाद रथ के पहिये थके हुए हैं। पर नंदिनी सत्पथी थकी नहीं हैं। उन्होंने पटनायक को उखाड़ फेंकने की शपथ ले रखी है। इसलिए वे पटनायक विरोधियों को जोर-शोर से बटोरने में जुटी हैं। पटनायक के इन्हीं प्रबल विरोधियों में एक पूर्व मंत्री वसंत कुमार बिस्वाल आजकल नंदिनी सत्पथी के प्रमुख सिपहसालार हैं। १९८५ तक वसंत बिस्वाल मुख्यमंत्री पटनायक के नाक के बाल थे। कहते हैं कि वसंत बिस्वाल ही पटनायक के खजाने व खाते-बही का हिसाब-किताब रखते थे। पर बाद में पटनायक उनसे इस हद तक नाराज हुए कि गत विधानसभाई चुनाव में उन्होंने वसंत का टिकट तक कटवा दिया। फिर भी कुछ दिनों तक दोनों के संबंध की डोर जुड़ी रही, पर आखिरकार वसंत बिस्वाल पटनायक के विरुद्ध खुलकर सामने आ गये। जिन दिनों वसंत पटनायक के चहेते मंत्री हुआ करते थे, उस समय लेंका को भी कई बार उन्होंने उपेक्षित किया था। लिहाजा, लेंका भी उनसे पहले से खार खाये बैठे थे। वसंत बिस्वाल उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर थे, पर जब लेंका ने अपनी कमेटी बनायी, तो वे वसंत को किसी सूरत में रखने को तैयार नहीं हुए। जबकि लेंका ने अन्य प्रबल पटनायक विरोधी गंगाधर महापात्र तथा हेमानंद बिस्वाल को खुशी-खुशी प्रदेश संगठन में पद दिया। वसंत से पटनायक का तनाव बाद में इतना गहरा गया कि पटनायक ने 'उड़ीसा ओलंपिक एसोसिएशन' के अध्यक्ष पद से भी वसंत की छुट्टी करवा दी। पटनायक ने वसंत के मुकाबले ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में अपने एक मंत्री जदुनाथ दास को खड़ा कर दिया और वसंत को पटकनी खिलवा दी। इस तरह पटनायक तथा लेंका दोनों के द्वार वसंत के लिए बंद हो गये, तो वसंत के पास नंदिनी सत्पथी का झंडा थामने के सिवा और कोई विकल्प भी नहीं रह गया था। इसलिए २९ मार्च को जब प्रदेश कांग्रेस की ओर से नंदिनी सत्पथी पर कार्रवाई करने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ, तो साथ-साथ वसंत बिस्वाल को भी पार्टी से निकालने की मांग प्रस्ताव के जरिये की गयी थी। वसंत बिस्वाल 'माया' से कहते हैं, "इस प्रस्ताव के बारे में मैं क्या कहूं? इसके बारे में जानकी बाबू और लेंकाजी से पूछिए।" पिछले दिनों वसंत बिस्वाल को राजीव गांधी से जब मिलने का समय मिल गया, तो भुवनेश्वर के राजनीतिक गलियारों में सब चौंक गये।

यों, पटनायक को मात देना आसान नहीं। विगत दस वर्षों से जोड़तोड़ कर वे यों ही नहीं अपनी गद्दी पर बरकरार हैं। इसलिए यह लड़ाई भीषण और मारक होगी। नंदिनी सत्पथी बस एक मुद्दा जोर-शोर से लेकर चला रही हैं कि आगामी चुनाव पटनायक के नेतृत्व में अगर यहां लड़ा गया, तो कांग्रेस का अवशेष भी यहां नहीं बचेगा।

क्या पटनायक विरोधी मुहिम में नंदिनी को विधायकों-सांसदों या पटनायक मंत्रिमंडल के क्षुब्ध मंत्रियों का समर्थन मिल रहा है? नंदिनी समर्थकों का दावा है कि गंगाधर महापात्र, हेमानंद बिस्वाल सरीखे विधायक जहां उनके खेमे में हैं, वहीं पटनायक मंत्रिमंडल के मंत्री शरद पंडा, हरिहर करण, शेख मतलूब अली आदि भी परोक्ष रूप से इस खेमे के साथ हैं। एक पुराने राजनीतिज्ञ कहते हैं कि शेख मतलूब अली को उड़ीसा की राजनीति में 'मतलब अली' भी कहा जाता है। दरअसल, मतलूब जैसे कई मंत्री हैं जो गुपचुप नंदिनी सत्पथी के दरबार में भी सलामी बजाते रहते हैं। ताकि अगर नंदिनी के दिन चमकें, तो वे लोग अंधेरे में न रह जायें। उड़ीसा से कांग्रेस के २० सांसद हैं, जिनमें नंदिनी खेमे का दावा है कि उनके साथ संभलपुर जिले के सांसद कृपासिंधु भोई, बलांगीर जिले के सांसद तथा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नित्यानंद मिश्र, श्रीवल्लभ पाणिग्रही तथा लक्ष्मण मलिक हैं। कृपासिंधु भोई नंदिनी-मंत्रिमंडल में जहां खनन मंत्री हुआ करते थे, वहीं लक्ष्मण मलिक नंदिनी मंत्रिमंडल के लोक निर्माण मंत्री थे। दिल्ली में नंदिनी की यही लाबी है। हां, धवन के आगमन ने भी नंदिनी को मजबूती दी है। माखनलाल फोतेदार व जार्ज पटनायक की लाबींग करते हैं। नंदिनी खेमे के एक विधायक का कहना है कि पटनायक सिर्फ उड़ीसा के नेताओं पर ही लाबींग के लिए निर्भर नहीं करते। वे तो सभी प्रांतों के दिग्गज नेताओं से संबंध बनाकर उन सबसे मदद पाते हैं।

बहरहाल, गुजरे महीनों में अकसर अपने पक्ष में विधायकों की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए नंदिनी सत्पथी भुवनेश्वर स्थित अपने यूनिट-छह वाले सरकारी आवास पर भोज का आयोजन करती रही हैं। फरवरी के अंतिम सप्ताह और फिर अप्रैल माह में जब नंदिनी ने विधायकों को भोज दिया, तो राजनीतिक हलके में उसकी जबर्दस्त चर्चा रही।

१९८५ के विधानसभाई चुनाव के बाद उड़ीसा में पटनायक के विरुद्ध जो विक्षुब्ध गतिविधियां शुरू हुई थीं, वे १९८७ तक आते-आते बिलकुल द हो गयी थीं। उड़ीसा राजनीति के एक पुराने जानकार 'माया' से कहते हैं कि इसकी एक वजह यह भी थी कि जिन नेताओं ने विद्रोह का झंडा थामा था, उनकी अंग्रेजी दुरुस्त नहीं थी। इसलिए दिल्ली दरबार में वे लोग अपनी बात मजबूती से रख पाने में असफल रहे। उड़ीसा राजनीति के इस ज्ञाता के मुताबिक कांग्रेस की राजनीति में शुरू में बीजू पटनायक तथा बाद के दिनों में नंदिनी सत्पथी और जानकीवल्लभ पटनायक इसलिए शिखर पर पहुंचे, क्योंकि इन लोगों की अंग्रेजी काफी अच्छी थी। बहरहाल, अंग्रेजी में दक्ष राजनेता नंदिनी सत्पथी अब जबकि कांग्रेस में वापस आकर पटनायक का झंडा गिराने पर तुली हैं, तो असंतुष्टों को उम्मीद है कि शायद कुछ सफलता मिले। यों पटनायक को मात देना आसान नहीं। विगत दस वर्षों से जोड़-तोड़ कर वे यों ही नहीं अपनी गद्दी पर बरकरार हैं। इसलिए यह लड़ाई भीषण और मारक होगी। नंदिनी सत्पथी बस एक मुद्दा जोर-शोर से लेकर चला रही हैं कि आगामी चुनाव पटनायक के नेतृत्व में अगर यहां लड़ा गया, तो कांग्रेस का अवशेष भी यहां नहीं बचेगा। नंदिनी विगत उपचुनावों में कांग्रेस की हार का हवाला भी दे रही हैं। एक असंतुष्ट कांग्रेसी नेता 'माया' से कहते हैं, "आगामी चुनाव में उड़ीसा में पटनायक के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या गति होगी, इसका परिणाम तो भगवान जगन्नाथ ने पुरी के कार्यक्रम में पहले ही दे दिया है। पिछले दिनों जगन्नाथ मंदिर के समीप पुरी में चुनावी तैयारी की शुरुआत के रूप में सभा के लिए मंच तैयार किया गया। इस मंच पर जानकीवल्लभ पटनायक, कान्हूचरण लेंका, केंद्रीय राज्यमंत्री चिंतामणि पाणिग्रही तथा सांसद ब्रजमोहन मोहंती आकर विराजमान हुए कि मंच ही टूट गया। सबके सब गिरते-गिरते बचे।"

—विकास कुमार झा

स्टेट्समैन बनाम सतीश शर्मा

बहुमंजिली इमारत अधर में

क्या कैप्टन सतीश शर्मा ने 'स्टेट्समैन' के कार्यकारी प्रबंध निदेशक सीआर ईरानी को वाकई धमकी दी थी ? या ईरानी प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ में अपना मकसद निकालने के लिए किस्से गढ़कर शोर मचा रहे हैं ?

"मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसे निम्न स्तरीय बदले की भावना से काम करेगा"—'स्टेट्समैन' के कार्यकारी प्रबंधक सीआर ईरानी।

प्रधानमंत्री के मित्र और सांसद कैप्टन सतीश शर्मा एक बार फिर विवादों की सुर्खियों में हैं। यद्यपि इस बार आरोप इतालवी टाइलों के आयात, मित्र व्यापारी ललित सूरी की गैरकानूनी रूप से मदद करने अथवा श्रीमती सोनिया गांधी से मिल कर ताबूतों के आयात का धंधा करने का नहीं। इस बार आरोप यह है कि कैप्टन शर्मा ने दिल्ली और कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले अंग्रेजी दैनिक 'द स्टेट्समैन' के प्रबंध निदेशक सीआर ईरानी को तथाकथित धमकी दी। ईरानी के अनुसार कैप्टन 'स्टेट्समैन' से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि 'स्टेट्समैन' ने कैप्टन के मित्र ललित सूरी द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक टेण्डर में अनधिकृत कमीशन लेने का भंडाफोड़ किया था। ईरानी कहते हैं कि २ अगस्त, १९८८ को कैप्टन शर्मा ने संदेश भेजा कि वे कैप्टन से मिलें अन्यथा 'स्टेट्समैन' के भवन-निर्माण के प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किये जायेंगे, 'स्टेट्समैन' के स्वामित्व की पूरी छानबीन की जायेगी, ताकि वर्तमान स्वामियों को हटाकर 'स्टेट्समैन' पर कब्जा किया जा सके, ईरानी की आयकर फाइलों से कुछ-न-कुछ ढूंढ़ निकाला जायेगा तथा ईरानी की विदेश यात्राओं की पूरी जांच होगी, ताकि उन पर 'फेरा' (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सके।

सतीश शर्मा

अब आरोप यह है कि कैप्टन सतीश शर्मा ने दिल्ली और कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले अंग्रेजी दैनिक 'द स्टेट्समैन' के प्रबंध निदेशक सीआर ईरानी को तथाकथित धमकी दी। ईरानी के अनुसार कैप्टन 'स्टेट्समैन' से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि 'स्टेट्समैन' ने कैप्टन के मित्र ललित सूरी द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक टेण्डर में अनधिकृत कमीशन लेने का भंडाफोड़ किया था।

आरोप-प्रत्यारोप : यद्यपि ईरानी का कहना है कि धमकियों पर अमल शुरू हो गया है, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा के नजदीकी सूत्रों के अनुसार ईरानी जानबूझकर मामले को राजनीतिक तूल दे रहे हैं। उनके अनुसार ईरानी ने कैप्टन पर आरोप इसलिए लगाया है, ताकि सरकार 'स्टेट्समैन' के प्रस्तावित भवन को स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाये, यानी कानूनी आधार पर भवन-निर्माण को स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो ईरानी यह शोर मचा सकें कि कैप्टन शर्मा के दबाव में उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उनका कहना है कि कैप्टन शर्मा ने ईरानी को कोई धमकी नहीं दी है। एक जानकार सूत्र का कहना है कि स्वयं ईरानीं कैप्टन शर्मा से मिलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अनेक संदेश कैप्टन तक पहुंचाये। पर जब कैप्टन ने मिलने से इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ मुहिम चालू कर दी।

मजेदार बात तो यह है कि स्वयं 'स्टेट्समैन' के कुछ कर्मचारी भी यह मानने को तैयार नहीं कि कैप्टन शर्मा ने ईरानी को कोई धमकी दी। वे इस सिलसिले में ईरानी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र की ओर संकेत करते हैं। पत्र में ईरानी ने लिखा था कि उन्हें २ अगस्त, १९८८ को संदेश मिला कि वे कैप्टन सतीश शर्मा से चाय पर मिलें, प्रधानमंत्री चाहते हैं। उनका कहना है कि ईरानी ने न तो संदेशवाहक का नाम बताया, न ही यह बताया कि कैप्टन शर्मा ईरानी से क्या चाहते थे। यदि कैप्टन शर्मा ने धमकी दी भी, तो वे २ अगस्त, १९८८ से चुप क्यों थे ?

कुछ अन्य कर्मचारी यह तो मानने को तैयार हैं कि कैप्टन शर्मा ने ईरानी को धमकी दी, पर उनका मत है कि जिस प्रकार ईरानी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख तुरंत प्रेस कांफ्रेंस बुला कर प्रचार किया, उससे उनके मंशा पर संदेह होता है। कुछ ऐसा ही मत 'स्टेट्समैन' के भूतपूर्व संपादक एस सहाय का है। सहाय के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता और आर्थिक व अन्य अपराध अलग-अलग मुद्दे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का उपयोग आर्थिक अपराधों को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता, पर सहाय यह बताने को तैयार नहीं कि ऐसे कौन से आर्थिक अपराध हैं, जिनको ईरानी प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ में छिपा रहे हैं ?

बहरहाल, यह मामला आज का नहीं, नौ वर्ष से चला आ रहा है। 'स्टेट्समैन' दिल्ली का वर्तमान भवन दिल्ली के सबसे महंगे स्थान कनाट प्लेस में स्थित है और ईरानी इस भवन को गिरा कर उसके स्थान पर एक बहुमंजिली इमारत बनाना चाहते हैं। मई, १९८० में 'स्टेट्समैन' ने नयी इमारत का नक्शा नयी दिल्ली नगर पालिका को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था। २९ अगस्त, १९८० को नगर पालिका ने प्रस्ताव पास कर दिया, पर मंजूरी सिर्फ

दो वर्ष के लिए वैध थी। 'स्टेट्समैन' के अनुसार उसे मंजूरी की सूचना ४ मई, १९८२ को मिली। अर्थात पौने दो साल बाद। चूंकि तीन महीने में भवन-निर्माण नहीं किया जा सकता था, अतः दूसरा प्रस्ताव नगर पालिका को भेजा गया। प्रस्ताव १८ मई, १९८४ को पास कर दिया गया, पर मंजूरी की सूचना वैधता की अवधि समाप्त होने के कुछ ही सप्ताह पूर्व दी गयी। इस बीच जनवरी, १९८५ में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी गयी। कनाट प्लेस क्षेत्र के लिए यह रोक १८ जुलाई, १९८६ को रद्द कर दी गयी। दिसंबर १९८६ में नये प्रस्ताव नगर पालिका को भेजे गये। पर १८ फरवरी, १९८७ को नगर पालिका के मुख्य वास्तुकार ने प्रस्ताव को २८ तकनीकी खामियों के कारण रद्द कर दिया। मई, १९८७ में 'स्टेट्समैन' ने एक और प्रस्ताव नगर पालिका को भेजा। मई, १९८८ में नगर पालिका ने तीन खामियां ६० दिन के भीतर पूरी करने को कहा।

ईरानी के अनुसार सारी खामियां दूर कर दी गयीं और नगर पालिका प्रस्ताव पास करने ही वाली थी कि पालिका के अधिकारियों को 'ऊपर' से आदेश प्राप्त हुआ कि प्रस्ताव पास न किये जायें। नगर पालिका के अधिकारी ईरानी के आरोप को बेबुनियाद बताते हैं।

किंतु मामले ने तूल तब पकड़ा जब २७ अगस्त, १९८८ को नगर पालिका ने 'स्टेट्समैन' के वे भाग 'सील' कर दिये जहां नयी इमारत के लिए बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य चल रहा था। ५ अक्तूबर, १९८८ को 'स्टेट्समैन' को इस आशय की एक नोटिस और मिली कि वे २४ घंटे के भीतर नये निर्मित भाग को गिरा दें। ईरानी के अनुसार आश्चर्य की बात तो यह है कि २७ अगस्त, १९८८ को शनिवार तथा रक्षाबंधन के त्यौहार के कारण छुट्टी थी, किंतु उस दिन 'स्टेट्समैन' को नोटिस देने के लिए खासतौर से नगर पालिका का दफ्तर खुला। नगर पालिका सूत्रों के अनुसार शनिवार को दफ्तर खुलना सामान्य बात है, पर बिना अनुमति 'स्टेट्समैन' का निर्माण शुरू करने का क्या हक था?

'स्टेट्समैन' दिल्ली का
वर्तमान भवन दिल्ली के सबसे महंगे
स्थान कनाट प्लेस में
स्थित है और ईरानी इस भवन
को गिरा कर उसके
स्थान पर एक बहुमंजिली इमारत बनाना
चाहते हैं।

अदालती लड़ाई : अंततः मामला दिल्ली की तीस हजारी अदालत तथा बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा। उच्च न्यायालय ने माना कि नगर पालिका बेबुनियाद आपत्तियां उठा मामले को लटका रही है। नगर पालिका की आपत्ति थी कि आग लगने की स्थिति में वर्तमान नक्शे के अनुसार बहुमंजिली इमारत सुरक्षित नहीं होगी। पर मुख्य शमन अधिकारी ने स्वयं अदालत में उपस्थित होकर भवन को अपनी मंजूरी दे दी। न्यायालय ने नगर पालिका को आदेश दिया कि वह तुरंत 'स्टेट्समैन' भवन के निर्माण को स्वीकृति दे। किंतु नगर पालिका को यह मंजूर नहीं था। अतः उसने उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खटखटाये। नगर पालिका के वकील कपिल सब्बल की दलील थी कि मुख्य शमन अधिकारी की स्वीकृति से नगर पालिका बाध्य नहीं है तथा नगर पालिका की स्वीकृति के लिए सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। 'स्टेट्समैन' के वकील एफएस नारीमन का कहना था कि नगर पालिका द्वारा उठायी गयी सभी आपत्तियों को दूर कर दिया गया है। किंतु वह हर बार नयी आपत्तियां उठाती जा रही है। इस पर नगर पालिका के वकील की दलील थी कि यदि नगर पालिका पहले किसी गलती से कोई चूक कर बैठी हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह चूक बनी रहने दी जाये।

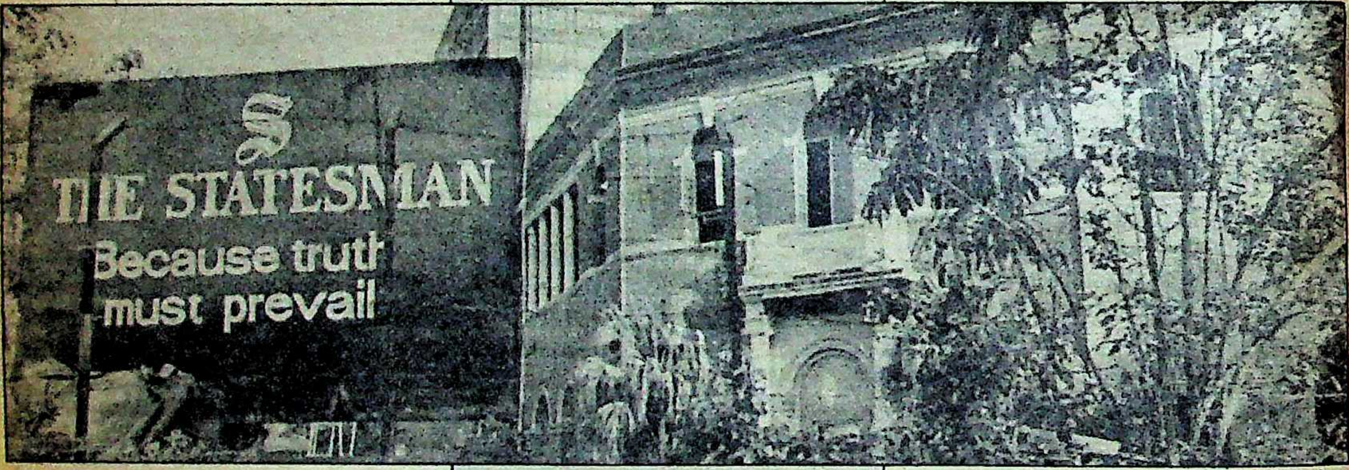

छाया : सुनील सक्सेना

शायद यह
विवाद बना रहेगा कि
क्या कैप्टन सतीश शर्मा ने
'स्टेट्समैन' को
धमकी दी? यदि नहीं, तो क्या
ईरानी अपनी प्रेस की शक्ति का
दुरुपयोग कर रहे हैं?

इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उच्चतम न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए ११ जुलाई, १९८९ की तिथि निश्चित की है और फैसला किसके पक्ष में जाता है, इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। पर तब तक और शायद उसके बाद भी यह विवाद बना रहेगा कि क्या कैप्टन सतीश शर्मा ने 'स्टेट्समैन' को धमकी दी? यदि नहीं, तो क्या ईरानी अपनी प्रेस की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं? कैप्टन शर्मा के एक करीबी सूत्र का कहना है कि 'स्टेट्समैन' के भवन का मामला १९८० से लटका है। उस समय कैप्टन शर्मा राजनीतिक पटल पर भी नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में ईरानी ने दोटूक सवाल किया है, "क्या कैप्टन शर्मा इतना खुले आम 'स्टेट्समैन' को धमकाते, यदि उन्हें लगता कि उन्हें आपका समर्थन नहीं हासिल है?" पर प्रधानमंत्री के समर्थन की बात तो तभी उठती है, जब यह सिद्ध हो जाये कि कैप्टन सतीश शर्मा ने उनको धमकी दी। अभी तो ईरानी यह भी बताने को तैयार नहीं कि किस व्यक्ति को माध्यम बनाकर यह धमकी दी गयी? जब तक ईरानी पूरे रहस्य से परदा उठा सच्ची बात नहीं बताते, शक की सुई उन्हीं की ओर होगी।

—अभय अग्रवाल

नगर
उसने
। नगर
थी कि
ालिक
कृति के
री है।
कहना
ी सभी
वह हर
इस पर
दि नगर
कर बैठी
ी रहने

च्चतम
जुलाई,
किसके
करेगा।

ल सक्सेना

विवाद
ार्मा ने
तो क्या
कर रहे
ना है कि
लटका
पर भी
पत्र में
न शर्मा
दि उन्हें
न है ?"
ठती है,
शर्मा ने
बताने
बनाकर
हस्य से
की सुई

अग्रवाल

प्रतिबंध?
इसलिए कि इसमें ५३ से मि. एफ.एस.टी. है?
इसलिए कि यह वक़्त से कहीं आगे का टीवी है?
इसलिए कि इसमें दंग करने वाली ख़ूबियाँ हैं?
या सिर्फ़ इसलिए कि इसकी वजह से ईर्षा की
नई लहर उफ़न पड़ेगी?

ओनिडा २१

पड़ोसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान.

क्या नए
ओनिडा पर प्रतिबंध
लगाया जाए?

कला फिल्मों ने घुटने क्यों टेक दिये ?

व्यावसायिक फिल्मों की स्तरहीनता से ऊब कर
सत्तर के दशक में शुरू हुए कला फिल्मों के आंदोलन ने अस्सी के
दशक में दम क्यों तोड़ दिया ?

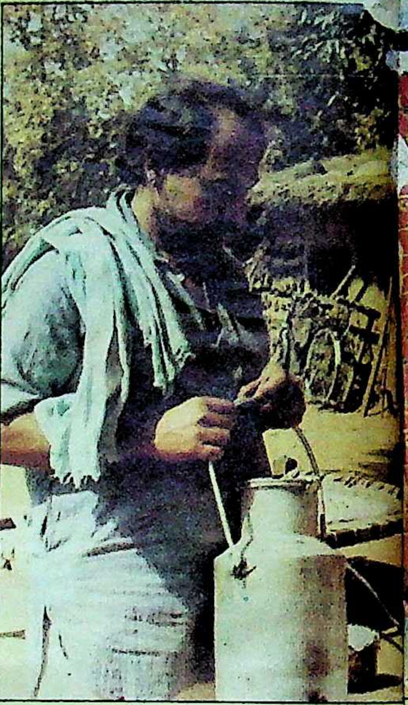

'देबशिशु' के एक दृश्य में साधु मेहर और रोहिणी

दो दशक पहले फेमस सिने लैब का मिनी थियेटर वितरकों, दलालों और अतिथियों से इस कदर भर गया था कि बैठने के लिए एक सीट तक नही बची थी, आधे से अधिक लोगों की भीड़ हाल में खड़ी होकर फिल्म का ट्रायल शो देखने के लिए विवश थी। यह ट्रायल शो था, मणि कौल की बहुचर्चित कला फिल्म 'उसकी रोटी' का, जिसकी तारीफ में उन दिनों पत्र-पत्रिकाओं के पन्ने भरे रहा करते थे। 'उसकी रोटी' के निर्माता रोचक पंडित काफी खुश थे कि वितरक उनकी फिल्म को वितरण के लिए खरीद लेंगे, लेकिन जब ट्रायल शो खतम होने पर मिनी थियेटर में उजाला हुआ, तो वहां सिवा रोचक पंडित तथा इन पक्तियों के लेखक के एक भी शख्स मौजूद नहीं था, फिल्म के निर्देशक मणि कौल भी नही। आधी फिल्म के बाद ही लोग एक-एक कर खिसकने लगे थे। रोचक पंडित के मन पर उस समय क्या बीती थी, हमें पता नही, लेकिन दूसरे दिन नाज सिनेमा बिल्डिंग में अपने आफिस में बैठा एक फिल्म वितरक फिल्म दलाल पर जरूर लाल-पीला हो रहा था—"काये कू तूने अपुन को वहां पे फंसा दिया ? वो बी कोई फिलिम थी ? हीरो-हीरोइन का पताच नहीं। बस, एक थोबडा का क्लोजअप क्या परदे पर आ गया, दस-दस मिनट तक हटनेच का नामीच नही ! डिरेक्टर तो प्रोड्यूसर को अक्खा डुबाइच देंगा..." कला फिल्मों की उपेक्षा का इससे बडा और क्या उदाहरण हो सकता है ?

सुखद शुरुआत : फिल्म निर्माताओं को ऋण मुहैया कराने के लिए १९६२ से '६९ तक फिल्म वित्त निगम (अब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम—एनएफडीसी) की न तो कोई निश्चित योजना थी, न सिद्धांत। उस समय तक केवल व्यावसायिक फिल्मों को ही ऋण दिये जाते थे। इसके तहत 'गोदान', 'चार धाम', 'अरमान भरा दिल', 'नवाब सिराजुद्दौला', 'अमर ज्योति', 'पुनर्मिलन', 'रंगमहल', 'दो दूनी चार', 'हीर-रांझा', 'संबंध', 'अनोखी बात' आदि फिल्मों को ऋण दिये गये। इन फिल्मों के फ्लाप हो जाने के कारण निगम द्वारा दी गयी कर्ज की सारी राशि जो लाखों में थी, डूब गयी। बाद में जब जाने-माने पत्रकार बीके करंजिया निगम के पांचवें अध्यक्ष बनाये गये, तो उन्होंने इस बारे में निगम के संचालकों के साथ विचार-विमर्श कर कर्ज देने की एक निश्चित नीति तथा योजना तैयार की। इस नीति के तहत तीन युवा फिल्मकारों—मृणाल सेन ('भुवन शोम'), बासु चटर्जी ('सारा आकाश') तथा कांतिलाल राठौड़ ('कुंक'-गुजराती) को फिल्म बनाने के लिए ऋण दिये गये। इन तीनों फिल्मों की सफलता ने युवा प्रतिभाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और फिल्म कला माध्यम में एक नये युग का सूत्रपात हुआ।

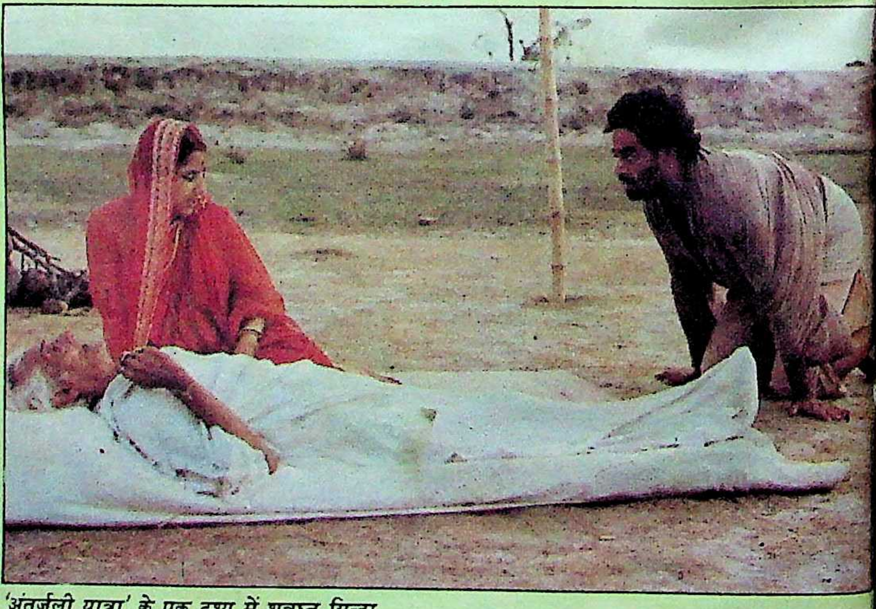

'अंतर्जली यात्रा' के एक दृश्य में शत्रुघ्न सिन्हा

निगम की इस नीति ने युवा फिल्मकारों की ही नही, बहुत से लेखकों की कृतियों को सेल्यूलाइड पर लाने में सहायता की। निगम से ऋण लेने के लिए नव फिल्मकारों ने प्रख्यात लेखकों की कृतियों को अनुबंधित करना शुरू किया—जैनेंद्र कुमार ('त्यागपत्र') से लेकर कमलेश्वर ('सारा आकाश', 'बदनाम बस्ती', 'फिर भी' आदि) तक दर्जनों जाने-माने कथाकारों की कृतियां प्रकाश की आलमारियों से निकल कर सेल्यूलाइड के प तक पहुंच गयीं।

१९६९ से '७४ का दौर (विशेषकर शुरू दो वर्ष) कला फिल्म आंदोलन के तीव्र विकास दौर था। अमरीका में रह रहे अवतार कृष्ण क '२७ डाउन' बनाने के लिए विशेष रूप से व आये। कला फिल्मों की लोकप्रियता ने उस समय व्यस्ततम कलाकारों को भी आकर्षित किय वहीदा रहमान ('त्रिसंध्या'), राखी (

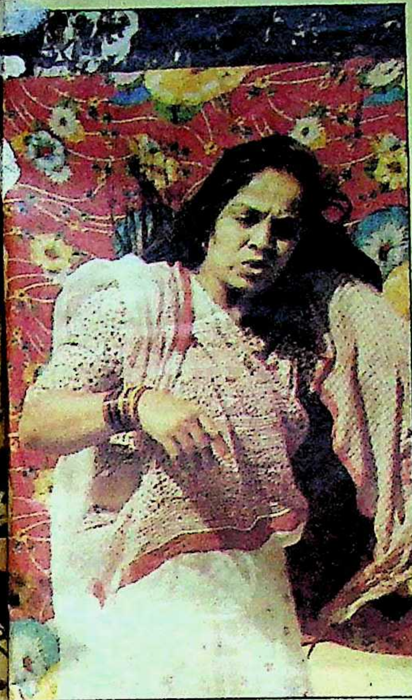

'परिणति' का एक दृश्य

स्टनजी' में किरण ठाकुर और नसीरुद्दीन शाह

ड़न'), सिमी ग्रेवाल ('डाक बंगला'), जाहिरा 'आक्रांत'), विद्या सिन्हा ('त्यागपत्र'), संजीव मार ('अनुभव'), राजेश खन्ना-शर्मिला ठाकुर 'आविष्कार') और बिंदू ('डाकू') ने अपनी पूरी स इन फिल्मों को दीं, यही नहीं इन लोगों ने रिश्रमिक भी नाममात्र को लिये।

इस दौर में मणि कौल सर्वाधिक चर्चित रहे र उन्हें न्यू वेव सिनेमा का अगुआ मान लिया ा, लेकिन वे एक विशिष्ट दर्शक वर्ग नहीं बना के। उन्होंने सिनेमा की भाषा को जो विस्तार दिया, आब्स्ट्रेक्ट पेंटिंग की तरह लोगों की समझ के परे साबित हुआ। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में उन फिल्मकारों को शिरकत करने तथा अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर आने का भरपूर मौका मिला।

दूसरा दौर: इसके बाद १९७४ में कला फिल्मों का दूसरा दौर श्याम बेनेगल ('अंकुर') के आगमन से हुआ, लेकिन १९७४ से १९८० तक कला फिल्म आंदोलन एक तरह से ठप पड़ा रह गया, क्योंकि कर्ज देनेवाली बैसाखी (एफएफसी) की अंदरूनी स्थिति डांवाडोल होने लगी थी। वह सिर्फ एक तरह की 'ब्रोकर' भर बनकर रह गयी थी। इसी दौरान बहुसितारीय तथा हिंसाप्रधान फिल्मों की लहर ने भी इसे काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान सिर्फ श्याम बेनेगल, बासु चटर्जी, गुलजार आदि कुछ फिल्मकार सिर्फ अपने बल पर डटे रहे और अपनी-अपनी शैलियों में फिल्में बनाते रहे।

कला फिल्मों के लिए यह बहुत संघर्ष का समय था। १९८० में, एनएफडीसी की स्थिति सुधरते ही, कला फिल्मों का पुनः उदय हुआ। इस काल की प्रमुख देन थे—गोविंद निहलानी जो अभी तक श्याम बेनेगल की यूनिट में कैमरामैन थे। १९८० में प्रदर्शित उनकी फिल्म 'आक्रोश' ने कला फिल्म आंदोलन को एक नयी दिशा दी। सत्याजित रे ने 'सद्गति', मृणाल सेन ने 'कफन' तथा 'खंडहर' जैसी फिल्में बनाकर नये सिनेमा को जीवित करने की पूरी कोशिश की। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई नये फिल्मकार प्रकाश में आये। इनमें प्रकाश झा ('हिप हिप हुर्रे'), कुंदन शाह ('जाने भी दो यारो'), जब्बार पटेल ('सुबह'), सईद मिर्जा ('अरविंद देसाई की अजब दास्तान' तथा 'अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है'), नीरद महापात्र ('मायामृग'), केतन आनंद ('होली', 'भवनी भवई' तथा 'मिर्च मसाला'), दिलीप चित्रे ('गोदाम'), विनोद चोपड़ा ('सजाये मौत') आदि नये फिल्मकारों का शुमार था।

'गर्म हवा' जैसी बहुचर्चित फिल्म बनानेवाले एमएस सथ्यू ने 'सूखा' तथा 'कहां-कहां से गुजर गया' जैसी फिल्में भी बनायीं। सागर सरहदी ने 'बाजार' तथा मुजफ्फर अली ने 'उमराव जान' बनाकर अपने लिये एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। कांतिलाल राठौड़ ने एक लंबे अरसे के बाद

महिलाओं की एकमात्र सम्पूर्ण पत्रिका

मनोरमा

जून प्रथम अंक

कैरियर, रोजगार विशेषांक

छात्राओं एवं गृहणियों के लिए
घर बैठे रोजगार के ५० अवसर

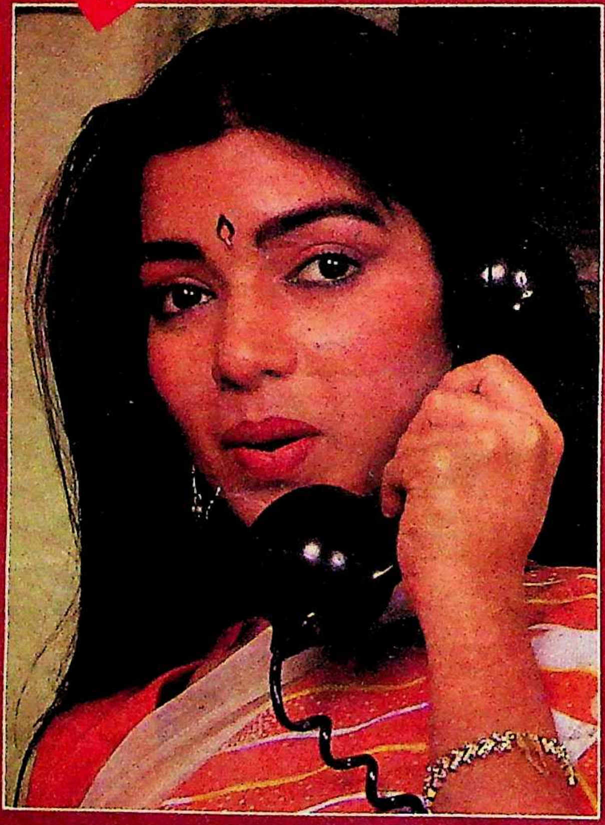

प्रमुख आकर्षण

- एड एजेन्सी में नौकरी
- घर बैठे रोजगार : कुछ प्रेरक महिलाएं
- एम०बी०ए० कोर्स कैसे करें?
- क्या आप भी लघु उद्योग शुरू करना चाह रही हैं?
- मास कम्यूनिकेशन : एक बहु उपयोगी कोर्स
- मुझे अपना कैरियर चुनने दें
- आफिस में आपके तौर-तरीके
- कैरियर गर्ल के लिए कैसा जीवन साथी चुनें?

आवरण कथा

क्या यह जरूरी है कि हर औरत आत्मनिर्भर हो?

साथ ही मेरी सुहागरात, सौन्दर्य, व्यंजन, हास्य-व्यंग्य, फैशन, फिल्म, चक्रव्यूह आदि स्थाई स्तंभ तथा एक लम्बी कहानी

आज ही अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

'रामनगरी' बनायी। कला फिल्मों ('रजनीगंधा') से फिल्म अभिनय की शुरुआत करनेवाले अमोल पालेकर ने अपने घटते मार्केट को देख कर अभिनय के साथ-साथ कला फिल्मों का निर्देशन एवं निर्माण भी शुरू कर दिया।

एक अलग धारा की शुरुआत : 'सारा आकाश' तथा 'रजनीगंधा' की व्यावसायिक सफलता ने बासु चटर्जी को कला फिल्म आंदोलन की मुख्य धारा से काट कर व्यावसायिक सिनेमा की उस धारा से जोड़ दिया, जिसकी शुरुआत व्ही शांताराम ('आदमी'), चेतन आनंद ('नीचा नगर') तथा विमल राय ('दो बीघा जमीन') ने की थी। उनकी परंपरा में उस समय हृषिकेश मुखर्जी ('मुसाफिर', 'गुड्डी', 'आनंद') चल रहे थे। आम फार्मूला फिल्मों तथा मनोरंजन के सतही नुस्खों से अलग हटकर इस परंपरा के लोग साफ-सुथरी सुरुचिपूर्ण फिल्में बनाने में विश्वास रखते थे और बड़े सितारों को लेकर फिल्में बनाते थे।

बासु चटर्जी को यह रास्ता ज्यादा सहज तथा कम जोखिमपूर्ण लगा। फलतः उनके पास फिल्मों की कतार लग गयी। 'रजनीगंधा' के प्रदर्शन में विलंब जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद वितरक-फायनेंसर तथा प्रदर्शक सिर्फ बासु के नाम को फिल्म के पूरा होने की गारंटी मानने लगे। 'पिया का घर' (१९७२) की सफलता ने उनकी स्थिति और भी मजबूत कर दी। 'उस पार' (१९७४) उनकी खुद की फिल्म थी जो बाक्स आफिर पर हलकी गयी थी, लेकिन 'छोटी सी बात' (१९७५), 'चितचोर' (१९७६), 'प्रियतमा', 'स्वामी', 'सफेद झूठ' (१९७७), 'दिल्लगी', 'खट्टा-मीठा', 'तुम्हारे लिये' (१९७८) 'अपने पराये', 'मनपसंद' (१९८०), 'जीना यहां' (१९८१) के बाद बासु की पकड़ धीरे-धीरे दर्शकों की नब्ज पर से ढीली पड़ने लगी। जिस तेजी से वे कला फिल्मों का दामन पकड़ कर सफलता की ऊंचाइयों तक चढ़े थे, कामर्शियल फिल्मों के अंधानुकरण ने उन्हें उसी धरातल पर ला खड़ा किया।

"बासु मीडियाकर थे," एक कला फिल्मकार ने 'माया' को बतलाया, "उन्होंने एफएफसी तथा फिल्म फोरम का भरपूर फायदा सिर्फ अपने कैरियर के लिए उठाया। जब उन्होंने फिल्म फोरम की स्थापना की, तो निःसंदेह उनका उद्देश्य सार्थक लगा था। उस समय वे उस सिनेमा की धज्जियां उड़ाया करते थे जिसके वे आज एक अंग हैं और उस नया सिनेमा आंदोलन के फतवे पढ़ा करते थे, जिससे उन्होंने 'सारा आकाश' तथा 'रजनीगंधा' की सफलता के बाद तुरंत किनारा कस लिया था। गुलजार इस मामले में उनसे कहीं ज्यादा ईमानदार थे। उन्होंने अपने को कभी नया सिनेमा आंदोलन से नहीं जोड़ा और न ही अपनी पहली फिल्म ('मेरे अपने') को कला फिल्म का नाम दिया था, जबकि 'मेरे अपने', 'अचानक' तथा 'कोशिश' विशुद्ध कलात्मक फिल्में थीं।"

'मिर्च मसाला' का एक दृश्य

'राव साहेब' में तन्वी आजमी

बाबूराम इशारा नया सिनेमा आंदोलन से कतई नहीं जुड़े थे, लेकिन सामाजिक बुराई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उनके भीतर जो तेवर पैदा किया था, वह नया सिनेमा आंदोलन का ही हिस्सा था। 'चेतना' (१९७०) तथा 'जरूरत' (१९७३) ने उनके इस तेवर को पूरी तरह से उभारा था और लगा था जो काम मणि कौल, कुमार शाहनी, कांतिलाल राठौड़ आदि फिल्मकार मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, उसे पूरा करने का दमखम इशारा में भरपूर है। लेकिन बहुत जल्दी उनका भी बासु की तरह मोह-भंग हो गया। (बासु चटर्जी एवं बाबूराम इशारा 'तीसरी कसम' के दौरान बासु भट्टाचार्य के सहायक थे) उन्होंने भी आंख मूंद कर व्यावसायिक फार्मूलावाली फिल्मों का निर्देशन शुरू कर दिया। बाद की कुछ फिल्मों ('चरित्र', 'हाथी के दांत', 'बाजार बंद करो', 'कागज की नाव', 'औरत का इंतकाम', 'द रेप') में उनके तेवर जरूर आक्रामक हो गये थे, लेकिन अपने इस बदले हुए तेवर में वे संवेदनशीलता खो चुके थे।

'तीसरी कसम' के एक लंबे अरसे के बाद बासु भट्टाचार्य ने जब 'आधे अधूरे' तथा 'उसकी कहानी' बनायी, तो नया सिनेमा आंदोलन को काफी बल मिला था। इसके बाद उन्होंने आपसी रिश्ते को लेकर फिल्में बनानी शुरू कर दीं और 'अनुभव' 'आविष्कार', 'गृह प्रवेश', 'संगत', 'मधुमालती' आदि फिल्में बना डालीं, लेकिन जो पकड़ उनकी 'अनुभव' तथा 'आविष्कार' में थी, वह बाद की फिल्मों में ढीली पड़ती गयी।

संक्रमण का दौर : १९७३-७४ का समय नया सिनेमा आंदोलन के लिए संक्रमण का दौर था, जब पश्चिम की न्यू वेव लहर काफी हद तक थम चुकी थी। मणि कौल, कुमार शाहनी ('माया दर्पण', 'तरंग' आदि) गिरीश वैद्य ('आक्रांत'), प्रेम कपूर ('बदनाम बस्ती'), राज मारब्रोस ('त्रिसंध्या') अतीत बनने की डगर पर आ गये थे। १९६९ से १९७४ के बीच बनी इनकी फिल्में कोई खास पहचान नहीं बना सकीं।

ठीक ऐसे ही समय कला फिल्मों की निर्माण शैली का एक नया अंकुर फूटा—श्याम बेनेगल के रूप में। उनकी फिल्म 'अंकुर' (१९७४) ने कला फिल्म आंदोलन के मृतप्राय शरीर में पुनः प्राण संचार किया। डाक्यूमेंट्री तथा विज्ञापन फिल्में बनानेवाले श्याम बेनेगल ने असली धरती और असली समाज के असली आम आदमी की जिंदगी को अपनी फिल्म का विषय बनाया, जहां रोमांस का धुंआ तो था, लेकिन कांतिलाल राठौड़ के 'परिणय' (शबाना आजमी-रोमेश शर्मा) तथा एचके वर्मा की 'कादंबरी' (शबाना-विजय अरोड़ा) जैसा रोमानी स्रोत नहीं था।

श्याम बेनेगल मानते थे कि आम आदमी की जिंदगी एक विशेष वर्ग के शोषण तथा शारीरिक दोहन से भरी जिंदगी है, जिसके प्रति जरूरत विद्रोह करने की है। उन्होंने श्रीमंतों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह तथा क्रांति के स्वर को बड़ी कुशलता से

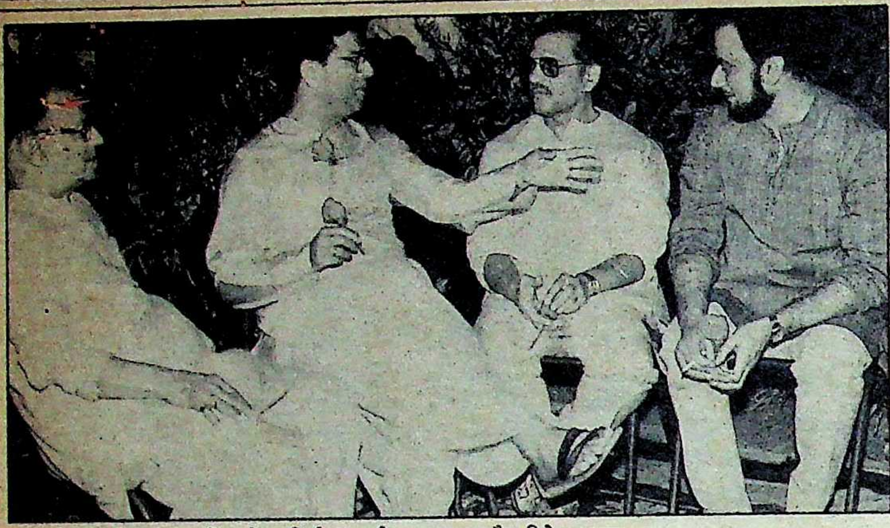

कला फिल्मों के स्तंभ: नबेंदु घोष, गिरीश कर्नाड, गुलजार और दिनेश ठाकुर

'अंकुर' (१९७४), 'निशांत' (१९७५), 'मंथन' (१९७७) तथा 'आरोहण' (१९८५) में उकेरा। 'भूमिका' (१९७७), 'कलयुग' (१९८१) तथा 'मंडी' (१९८३) उसी श्रीमंत एवं आभिजात्य समाज के भीतर की कड़वी सचाई थी जो समूची प्रभविष्णुता के साथ उजागर हुई थी। इसके विपरीत केए अब्बास ('नक्सलाइट') का तेवर कहीं अधिक पैना तथा सीधा आक्रमण करनेवाला था। इसीलिए 'नक्सलाइट' प्रतिबंधित कर दी गयी थी।

बासु भट्टाचार्य ने पति-पत्नी के अंतरंग रिश्तों के बीच पनपते तनाव को लेकर फिल्में ('अनुभव', 'आविष्कार', 'गृह प्रवेश') बनायी थी, लेकिन उस रिश्ते का एक और कसैला तथा अंधेरा पहलू भी था जिसे छूने तथा उस पर प्रहार करने की कोशिश उस महेश भट्ट ने 'अर्थ' (१९८३) 'जनम' (१९८६) तथा 'काश' (१९८७) बना कर की जो १९७३ से १९७९ के बीच 'मंजिलें और भी हैं', 'विश्वासघात', 'नया दौर' तथा 'लहू के दो रंग' जैसी सतही फिल्में बनाया करते थे। सामाजिक सचाई के प्रति प्रतिबद्धता की उनकी अपनी शैली है। 'सारांश' (१९८४), 'नाम' (१९८६), 'स्वयं' (१९८९) तथा 'मार्ग' (१९८८) इसी सामाजिक सचाई को अलग-अलग विद्रूपताओं के साथ पेश करती हैं।

श्याम बेनेगल के साथ एक लंबे अरसे तक कैमरामैन रहे गोविंद निहलानी ने सामाजिक शोषण तथा सचाई को और भी प्रखरता तथा तीव्र प्रहार के साथ 'आक्रोश' (१९८०), 'अर्द्धसत्य' (१९८३) 'पार्टी (१९८४), 'आघात' (१९८५) तथा 'तमस' (१९८८) में उकेरा। गोविंद निहलानी संवेदनशीलता के उस तरह कायल नहीं थे, जैसे श्याम बेनेगल थे। श्याम को विरोध की आंधी में भी गुलाब की सुगंध याद रहती थी, लेकिन गोविंद निहलानी के लिए गुलाब सिर्फ़ कांटेदार टहनियों से अलग कुछ मायने नहीं रखता था, इसीलिए 'अर्द्धसत्य' तथा 'तमस' का नायक अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ अंतरंग क्षणों में भी कोमलता का अहसास नहीं कर पाता, जबकि श्याम बेनेगल ने 'निशांत' तथा 'मंथन' में भी अंतरग तथा भावुकतावाली सिचुएशन का निर्माण किया है।

इसी प्रतिबद्धता की एक जीवंत तस्वीर हाल में मीरा नायर की फिल्मं 'सलाम बांबे' में देखने को मिली। न्यूयार्क में बसी युवा मीरा नायर ने भारत आकर पहले कैबरे नर्तकियों की जिंदगी पर 'इंडिया कैबरे' (१९८५), भ्रूण हत्या की विषमता पर 'चिल्ड्रेंस आफ डिजायर्ड सेक्स' (१९८७), जामा मस्जिद (दिल्ली) के पास रहनेवालों की अंदरूनी जिंदगी पर 'जामा मस्जिद' (१९७९), डाक्युमेंट्री फिल्में बनायी थीं। लेकिन 'सलाम बांबे' उनकी इन फिल्मों की शैली से जुड़कर भी फीचर फिल्म थी जिसमें वे बंबई महानगर की कड़वाहट को उजागर करना चाहतीं थीं। इसके लिए उन्होंने फुटपाथ, वेश्यालय तथा ऐसे ही गलीज कहे जानेवाले स्थलों की अंदरूनी जिंदगी को एक पात्र (कृष्णा) के माध्यम से पेश किया है। ठीक ऐसी ही एक फिल्म ('जागते रहो') राजकपूर भी बना चुके थे, लेकिन उनकी दुनिया अलग थी।

"कला फिल्मकार शुरू से ही दोहरी मानसिकता के शिकार रहे" सुरुचिपूर्ण फिल्में बनानेवाले एक निर्माता-निर्देशक 'माया' को बतलाते हैं, "उन्हें न तो नये सिनेमा के आंदोलन के प्रति निष्ठा थी, न ही कला फिल्मों के विकास के प्रति कोई लगन। १९६७-७० में अचानक ऐसे लोगों की जमात पैदा हो गयी जो खुद को इंटेलेक्चुअल बतलाते थे, समोवर में बैठकर अंतरराष्ट्रीय सिनेमा पर बहस करते थे।"

सिनेमाघर की किल्लत: "कला फिल्मों का विकास अवरुद्ध हो जाने का प्रमुख कारण था—कला थियेटरों का देश में अभाव," बासु चटर्जी ने 'माया' को बतलाया, "दरअसल फिल्म वित्त निगम ने फिल्मकारों को कला फिल्में बनाने के लिए ऋण तो दिये, लेकिन इस हकीकत को वे नजरअंदाज कर गये कि इन्हें दिखलाने के लिए छोटे थियेटरों की जरूरत है, जहां ऐसी फिल्मों में रुचि रखनेवाले दर्शक इन्हें देख सकें। ऐसे आर्ट थियेटरों के न होने के कारण ही फायनेंसर कला फिल्मों में पैसा लगाने के लिए तैया नहीं होते थे और वितरक इन्हें इसलिए सिनेमाघरों में रिलीज करने से कतराते थे कि टिकट खिड़की प उन्हें दर्शकों का मजमा एकत्र होने में संदेह था।"

१९६९ में बनी बासु चटर्जी की फिल्म 'सारा आकाश' पहली कला फिल्म थी जो देश के अधिकांश बड़े शहरों में सिनेमाघर का न केवल मुंह देख सकी थी, बल्कि व्यावसायिक रूप से सफल भी रही थी। इसका कारण था, राजश्री फिल्म्स के मालिक ताराचद बड़जात्या की साफ-सुथरी फिल्मों के प्रति रुझान और व्यावसायिक दूरदर्शिता। वे मानते थे कि इस तरह की फिल्में फार्मूला सिनेमा से उकताये दर्शकों को राहत प्रदान करेंगी। उनकी व्यावसायिक सूझ थी कि उन्होंने 'नो लास नो प्राफिट' के आधार पर इन फिल्मों को मैटिनी शो में बंबई के भीड़-भाड़ भरे सिनेमाक्षेत्र में स्थित ड्रीमलैं सिनेमा में प्रदर्शित किया। दूसरे सिनेमाघरों में टिकट न मिलने पर निराश तथा घर में दोपहर को खाली रहनेवाली गृहिणियों के लिए इसे जरू समझा, लेकिन इसके साथ मुख्य बात यह थी कि मैटिनी शो के लिए सिनेमाघरों के रेट दूसरे शो काफी कम होते थे। उन्होंने 'सारा आकाश' के उ प्रिंट को बंबई के दूसरे उपनगरों में, फिर दूसरे शह में मैटिनी शो में रिलीज किया। इस सफलता प्रभावित हो उन्होंने मिनी थियेटरों की एक श्रृंख बनायी। लगभग छह-सात वर्षों तक यह परंप चलती रही, लेकिन बहुसितारीय तथा हिंसाप्रध फिल्मों ने कला फिल्मों के प्रदर्शन को काफी धक् पहुंचाया—इन छोटे थियेटरों में दूसरी कार्मशिय फिल्में दिखलायी जाने लगीं।

मनमोहन देसाई ने 'माया' को बतलाय "अब तो वे सिनेमाघर भी तोड़े जाने लगे हैं, व्यावसायिक फिल्में रिलीज होती थीं। अब जब इ व्यावसायिक फिल्मों के लिए हाल नहीं मुहैया हों तो कला फिल्मों के लिए हाल कहां उपलब्ध होंगे रिलीज के जिस संकट से जहां पहले कला सिने जूझ रहा था, अब व्यावसायिक सिनेमा भी उस स्थिति में फंस गया है।"

मनमोहन देसाई बतलाते हैं, "कला फि कभी भी मरी नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से जीवि भी नहीं रही। सिर्फ सांस भर लेती रही। उसे बचा की जरूरत है।"

'सलाम बांबे' की व्यावसायिक सफलता पुनः प्राणसंचार किया, कला फिल्म आंदोलन निस्पंद शरीर में। नबेंदु घोष ('तृषाग्नि'), ब भट्टाचार्य ('पंचवटी'), मृणाल सेन ('एक दि अचानक') अमित खन्ना ('शेष'), विजया मेह ('पेस्टनजी') के अलावा अपर्णा सेन, 'बुद्ध दासगुप्ता आदि नव फिल्मकार इसे पुनः जीवि रखने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल फि वही उठता है—ये फिल्में अपनी पूरी सार्थकता बावजूद क्या सिर्फ डब्बे में बंद पड़ी रह जायेंगी? लोग कला फिल्म आंदोलन का मर्सिया पढ़ने के लि विवश हो जायेंगे?

—रवींद्र श्रीवा

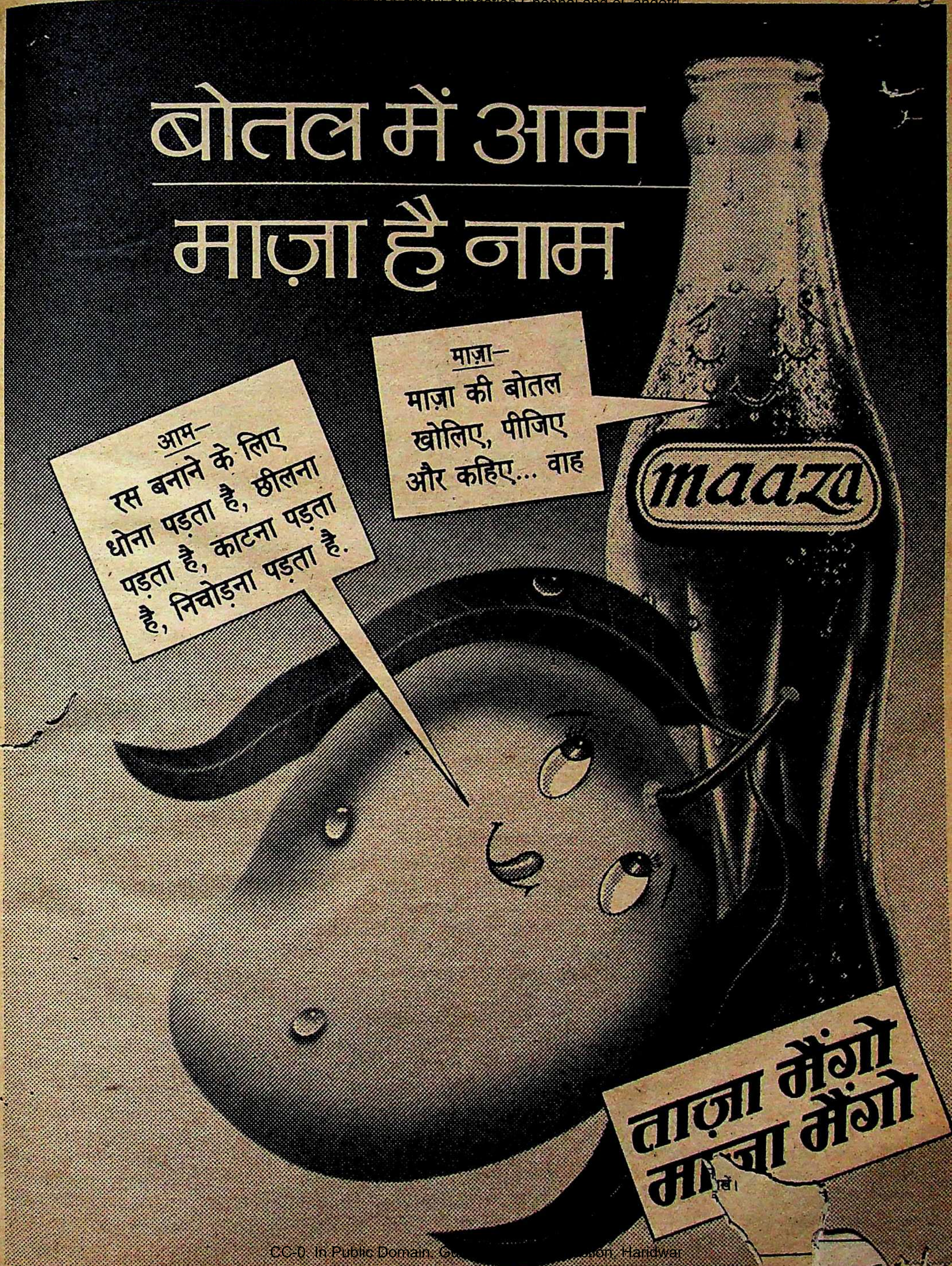
बोतल में आम
माज़ा है नाम
आम—
रस बनाने के लिए धोना पड़ता है, छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है.
माज़ा—
माज़ा की बोतल खोलिए, पीजिए और कहिए... वाह
maaza
ताज़ा मैंगो
माज़ा मैंगो

RADEUS/PE/MM/10-89-HIN

कोका कोला का दहला

कोका कोला ने एक और दांव मारा है। उसने पेप्सी कोला की तरह फल और रस का काम भी हाथ में लेने की पेशकश की है तथा थापर समूह को दो करोड़ रुपए मूल्य की बोतलें तैयार करने का आर्डर भी दिया है। मजे की बात यह है कि बोतलें तैयार हैं तथा थापर समूह बोतलों को बांग्लादेश भेजने का विचार कर रहा है। किंतु यदि इस बीच कोका कोला अपनी लड़ाई जीत जाता है, तो बोतलें उसके सुपुर्द कर दी जायेंगी।

जगदीश टाइटलर को पेप्सी कोला का समर्थन करते हुए देखकर कोका कोला ने दिनेश सिंह को अपना समर्थक बना लिया है। जाहिर है, दिनेश सिंह सिर्फ टाइटलर से सीनियर ही नहीं, कैबिनेट मंत्री भी हैं।

उल्लेखनीय है कि शुरू में कोका कोला ने दिल्ली के निकट निर्यात क्षेत्र में एक प्लांट लगाने और यहां बननेवाले माल का २५ फीसदी हिस्सा भारत में बेचने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारत सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। जबकि कोका कोला इस सीमा को १५ फीसदी तक घटाने को तैयार था और उसने यह भी तय कर रखा था कि अगर सरकार ने फिर इनकार किया, तो वह पेप्सी की तरह ही नया प्रस्ताव रखेगा, जिसे सरकार ठुकरा [illegible] नहीं पायेगी।

[illegible] या 'तमस' का [illegible]

कोका कोला [illegible] साथ अंतरंग [illegible] कोला का यु[illegible] हसास नहीं कर पाए पहुंच गया है। मजे की बात यह है कि जगदीश टाइटलर को पेप्सी कोला का समर्थन करते हुए देखकर कोका कोला ने दिनेश सिंह को अपना समर्थक बना लिया है। जाहिर है दिनेश सिंह सिर्फ टाइटलर से सीनियर ही नहीं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि कोका कोला को चुनाव होते ही अनुमति मिल जायेगी।

रुपए के बुरे दिन दूर नहीं

मजे की बात यह है कि शेयर बाजार में तो उफान आया हुआ है, किंतु रुपए की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में एक साल में रुपए की कीमत ५ से १७ फीसदी के बीच गिरी है। मिसाल के तौर पर अमरीकी डालर की तुलना में १७.०४ फीसदी, पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में ७.७७ फीसदी, जर्मन मार्क की तुलना में ५.६९ फीसदी और जापानी येन की तुलना में १२.२२ फीसदी रुपए की कीमत गिरी है।

दूसरी ओर यह भी खबर गर्म है कि १९८८-८९ में विदेश व्यापार में जितना घाटा हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। यह घाटा १०,००० करोड़ रुपए तक हो सकता है। उल्लेखनीय है कि घाटे की यह स्थिति निर्यात और आयात में जबरदस्त वृद्धि के बावजूद सामने आयी है। आयात-निर्यात का फासला साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। यह फासला जितना बढ़ता है, रुपए का मोल उतना ही कम हो जाता है। पिछले आठ वर्षों में रुपया अमरीकी डालर की तुलना में ५० फीसदी और येन के मुकाबले ५० फीसदी से थोड़ा ज्यादा गिरा है।

सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में चार साल बाद रुपए की क्या कीमत रह जायेगी? रिजर्व बैंक की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार १९९३ तक अमरीकी डालर ३०-३२ रुपए और पाउंड ५० रुपए तक का हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक अप्रवासी भारतीयों के लिए जारी अपने बांड का विज्ञापन इसी आधार पर कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तीन वर्षों में अमरीकी डालर २५ से २६ रुपए में बिकेगा।

कंपनियों की खरीद-फरोख्त जारी

जनवरी १९८८ से अब तक (१५ महीनों में) १६ कंपनियों की मिल्कियत बदल चुकी है। जिनमें से तीन विजय मलैया ने जो अब अप्रवासी हो गये हैं, दो अप्रवासी मनु छबरिया ने, तीन राम प्रसाद गोयनका ने, दो अभय ओसवाल ने और शेष धीरूभाई अंबानी, पीरामल और महिंद्रा परिवार ने खरीदी हैं।

एक मोटे अनुमान के अनुसार धीरूभाई अंबानी ने लार्सन ऐंड टुब्रो के लिए ८० करोड़ रुपए, यूनियन कारबाइड के लिए अभय ओसवाल ने ६० करोड़ रुपए, बर्गर पेंट्स के लिए विजय मलैया ने ३५ करोड़ रुपए, आईईएल की रिसड़ा इकाई के लिए अभय ओसवाल ने १४ करोड़ रुपए तथा मद्रास की स्पेंसर के लिए राम प्रसाद गोयनका ने ५ करोड़ रुपए दिये हैं।

अब सवाल यह है कि क्या कंपनियां खरीदने का खेल खतम हो गया है? जवाब है, अभी नहीं। एक और कंपनी के जल्द ही बिकने की खबर है। हालैंड की फिलिप्स कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी पेइको इलेक्ट्रानिक्स अपने आधे शेयर बेचना चाहती है। इसको तलाश है अप्रवासी खरीदार की। संभावित खरीदारों के रूप में मलैया और छबरिया सामने हैं। कंपनी कितनी कीमत में बिकेगी इसका अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही है और हो सकता है कि इस साल घाटा २५ करोड़ रुपए तक पहुंच जाये।

शेयर बाजार में तेजी का कारण

शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आयी हुई है। अप्रैल के महीने में बाजार ने नये कीर्तिमान बनाये और किसी-किसी दिन तो शेयर मूल्य सूचकांक तीन से चार फीसदी तक चढ़ गया। ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ हो। २१ अप्रैल को 'इकानामिक टाइम्स' शेयर मूल्य सूचकांक ३९९ से चढ़कर ४०९ पर पहुंच गया अर्थात २.५ फीसदी की वृद्धि हुई। यदि वृद्धि इसी रफ्तार से होती रही, तो सूचकांक इस वर्ष के अंत तक ५०० के ऊपर पहुंच सकता है और दलाल स्ट्रीट में पंजीकृत शेयरों के मूल्य में १०,००० करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है।

सवाल यह है कि शेयरों की कीमत में इतनी तेजी से बढोतरी क्यों हो रही है? मुद्रास्फीति, जिसकी अनुमानित वार्षिक दर अभी १० फीसदी है, इसका प्रमुख कारण है। कंपनियों के बढिया कामकाज की रिपोर्ट भी बढ़ोतरी का कारण है। लेकिन शेयर बाजार में तेजी का असली कारण शानदार फसल है जिससे किसानों के हाथ में करीब २०,००० करोड़ रुपए पहुंच गये हैं और पहली बार भारतीय किसान सोने की जगह शेयर खरीद रहा है। उल्लेखनीय है कि सोना एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी कीमत गिरी है। पिछले साल पहली अप्रैल को १० ग्राम स्टैंडर्ड सोना ३१८० रुपए का था। इस साल १७ मार्च को १० ग्राम सोना ३११५ रुपए में बाजार में उपलब्ध था।

शेयर बाजार में तेजी का कारण शानदार फसल है, जिससे किसानों के हाथ में २०,००० करोड़ रुपए पहुंच गये हैं और पहली बार भारतीय किसान सोने की जगह शेयर खरीद रहा है।

—डा० जय दुबाशी

आई.डी.बी.आई. के पूँजी-बांड पूँजी लाभ कर से छूट पाने का आकर्षक साधन

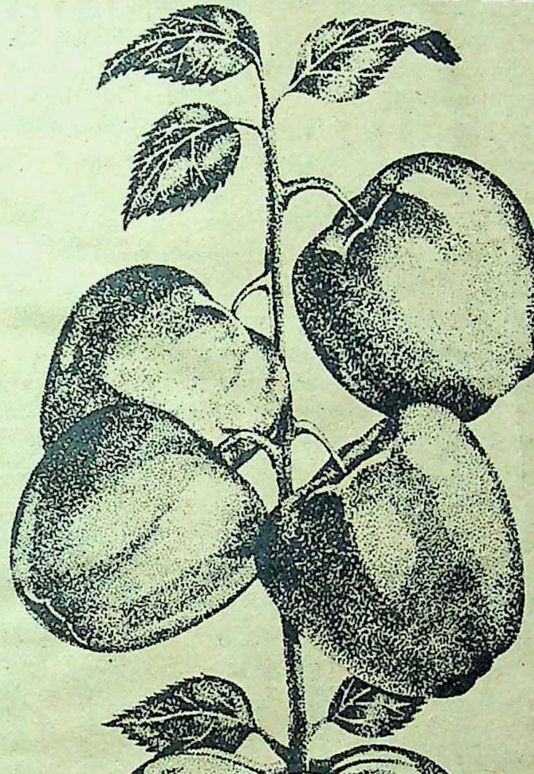

- पूरे वर्ष भर सम मूल्य पर उपलब्ध।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54E के अंतर्गत पूँजी लाभ कर से छूट।
- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1)(xvie) के अंतर्गत संपत्ति कर से छूट।
- धारा 80L. के अंतर्गत आय कर में लाभ।
- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। अर्ध-वार्षिक रूप से भुगतान।
- पूँजी निवेशक की इच्छानुसार 3 वर्ष की पूरी अवधि के ब्याज का डिस्काउंट आधार पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- स्त्रोत पर कर नहीं काटा जाता।
- बाहरी स्टेशनों के चेक स्वीकार किए जाते हैं। वसूली खर्च आई.डी.बी.आई. वहन करेगा।

25 1964-1989 SILVER JUBILEE YEAR

उद्योग की सेवा का 25 वाँ वर्ष

अधिक ब्योरे के लिए अपने निकटतम आई.डी.बी.आई. कार्यालय से संपर्क करें या प्रबंधक को लिखें।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

जॉली मेकर चेंबर्स नं. 2, 225, विनय के. शाह मार्ग, नरिमन पॉइंट, बम्बई 400 021.

Sobhagya-B/89 HN

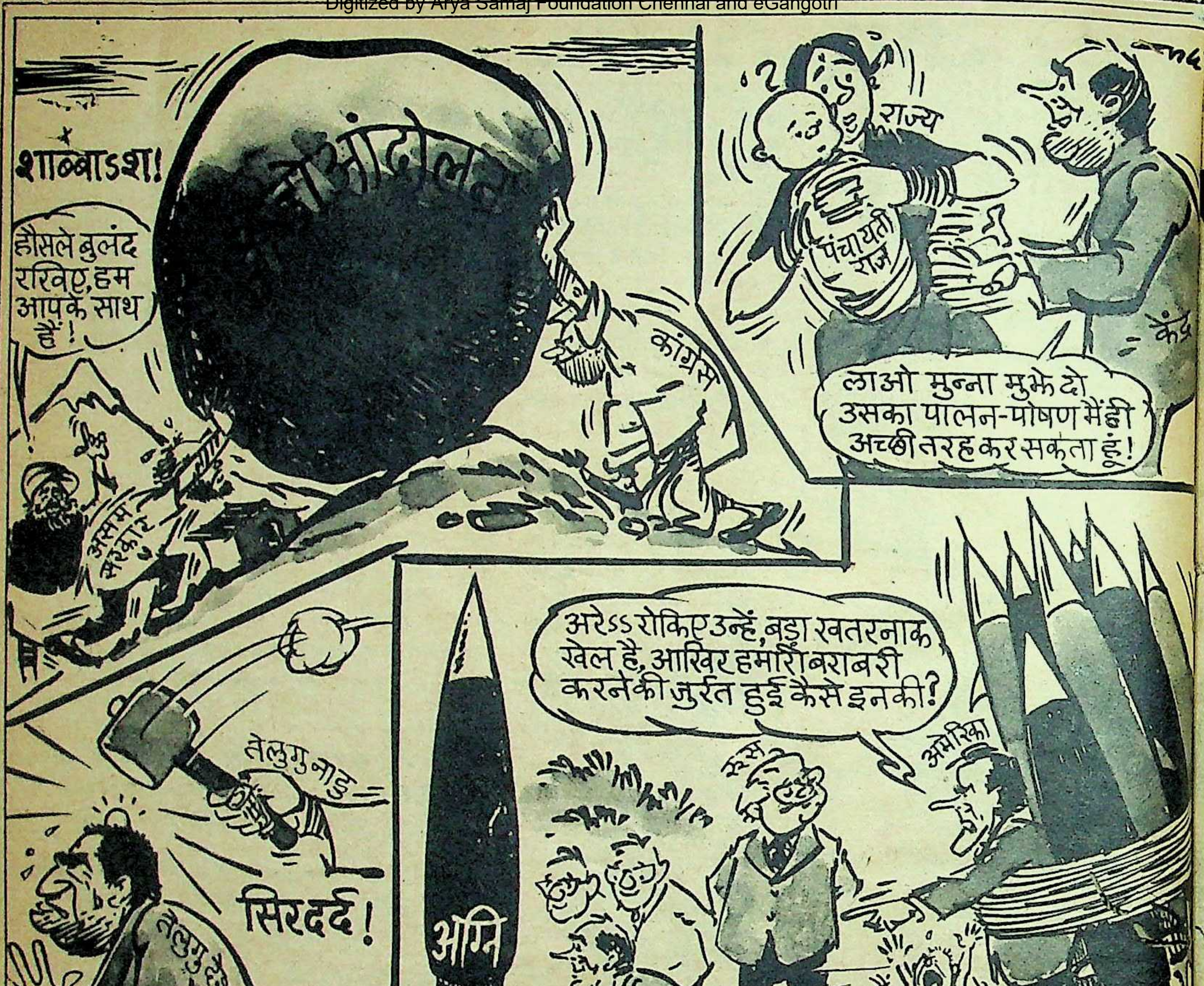
शाब्बाऽऽश!
हौसले बुलंद रखिए, हम आपके साथ हैं!
आंदोलन
कांग्रेस
असम सरकार
राज्य
पंचायती राज
केंद्र
लाओ मुन्ना मुझे दो उसका पालन-पोषण मैं ही अच्छी तरह कर सकता हूं!
तेलुगु नाडु
सिरदर्द!
तेलुगु देशम
आ.प्र. में एक और नए क्षेत्रीय दल तेलुगु नाडु की स्थापना—
अरेऽऽ रोकिए उन्हें, बड़ा खतरनाक खेल है, आखिर हमारी बराबरी करने की जुर्रत हुई कैसे इनकी?
रूस
अमेरिका
अग्नि
हाय, मैं मर गया!
पाक
विरोध
कांग्रेस
...पहले पीछे तो देखो अपने!

ला
हसास, न

पनो
अ

एक औ
परिवार
संघर्षों में
बाद इतना
उत्साह
पाता कि
र्माण बढ़ि
सके। घर
नौकर औ
जीवन
के साथ-
बहुत जो
में सब्र
लिए म

टूटे पनों की आहत आंखें

—ममता कालिया

पिछले दिनों देखे तीन छोटू! पहला छोटू बारह साल का! एक बुक बाइंडर के यहां काम करता था। किताबों की बंधाई, सिलाई और कटाई में मदद करना उसकी रोजमर्रा की ड्यूटी थी। छह महीने में काफी काम सीख गया था। एक रात उसने कटिंग मशीन का चक्का घुमाकर किताबों की गड्डी काटी, हस्बेमामूल। कटी-छंटी गड्डी वह उठाने ही लगा था कि मशीन का आरा अपने आप ऊपर जाने के बजाय धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसी के साथ आ गिरे छोटू के दो हाथ-तड़पते, फड़कते दो समूचे हाथ, हाथ जो उसकी रोजी-रोटी थे, उसके फटेहाल परिवार के मुह का निवाला थे, हाथ जिनकी बदौलत वह मजदूर से कारीगर बनने का हौसला रखता था। इन हाथों के रहते वह जगन्नाथ था।

आजकल वह एक अपाहिज का भविष्य लिये अस्पताल में पड़ा है। बाइंडिग हाउस का मालिक इस दुर्घटना की वजह छोटू की लापरवाही बता रहा है, जबकि बच्चे का कहना है कि कटिगं मशीन खराब थी, कई बार कहने पर भी ठीक नहीं करायी गयी थी।

दूसरा छोटू एक बड़े अस्पताल की कैंटीन में काम करता है। सबेरे छह बजे से रात ग्यारह बजे तक दौड़-दौड़ कर सब कमरों में चाय, नाश्ता, खाना पहुंचाना, खाली वक्त में सब्जियां काटना, कोयले तोड़ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के क्रेट संभालना और कैंटीन की मोटी मालकिन की झिड़की-घुड़की सुनना-सब उसकी ड्यूटी में शुमार है। रात में कैंटीन के बाहर गलियारे में जहां पंखा चलता है, वहीं अपना गमछा बिछा कर लुढक जाता है, नींद में बेसुध । उम्र बमुश्किल दस साल, प्यारा सुबुक चेहरा, गोरा रंग, भूरे बाल।

"कहां के हो?" पूछने पर उसकी आंखों में एक उदास बादल घिर आया।

"अल्मोड़ा। अब तो दो बरस हो गये घर से आये," उसका जोड़ीदार बताता है, "मां ने पानी का भरा मटका फूट जाने पर मार दिया था, बस तभी छोटू मेरे साथ भाग आया।"

"तुम उसे बहका कर लाये हो?"

"नहीं। यह अपने आप आया। कहता था, मां बहुत मारती है, अब मार नहीं खाऊंगा। हमने तो यहां काम दिलाया इसे।"

उसका साथी करीब सोलह साल का है, लेकिन उसकी आंखों में कैशोर्य का कोई कौतूहल नहीं है। जीवन के थपेड़े सहते—सहते वह इतना सावधान हो चला है कि हर सवाल का जवाब नहीं देता, जो निरापद समझता है, उसी का देता है। उसके संरक्षण और नेतृत्व में छोटू चुप-चुप रहता है, लेकिन अकेला मिलने पर सहज भाव से बोल उठता है। बता देता है कि मार कभी-कभी यहां भी पड़ जाती है, पर खाना भरपेट मिलता है, कोई रोकटोक नहीं है, जितना मर्जी खाओ।

तीसरा छोटू दर्जा चार में पढ़ता है। उसकी मां पास के किसी बंगले में आया है। मालकिन की शर्त है 'हमारा बच्चा पालते समय, अपना बच्चा नहीं पालना।' सो छोटू सारे दिन मां के सान्निध्य से वंचित अपनी सूनी कोठरी में बैठा लिफाफे बनाता रहता है। लोगों के घरों से तीन रुपए किलो पर रद्दी खरीद लेता है और लिफाफे बनाकर चार रुपए किलो बेच देता है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल लेता है। पढ़ने में तेज है, पढ़-लिख कर 'बड़े बाबू' बनना चाहता है। उसकी आंखों में निश्चय के नक्षत्र चमकते हैं।

यह सच है कि ये सभी बच्चे जिंदा हैं और अपने देश के नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल-रपट में इन बच्चों के आंकड़े अलग से नहीं मिलते, जिनका औसत न तो जन्मदर न मृत्युदर में आता है। अगर टूटे सपनों की आहत आंखों के आंकड़े इस रपट में होते तो इन छोटुओं की गिनती इस रपट में होती। बड़ी-बड़ी रिपोर्टों का निर्जीवीकरण इसी तरह होता है कि उनमें मानवीय आकलन की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

संयुक्त राष्ट्र बाल-रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष ने बालकों की जन्मदर पर तो नहीं, मृत्युदर पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है। अन्य एशियाई देशों में नवजात शिशुओं की मृत्युदर के आंकड़े दिल हिला देनेवाले हैं। असंख्य बच्चों को जन्म के पूर्व या पश्चात समुचित चिकित्सा या आहार नहीं मिल पाता। इससे बहुत से बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं अथवा प्रसव के समय मर जाते हैं। कुछ बच्चे असाध्य रोगी अथवा विकलांग के रूप में बड़े होते हैं। इस प्रकार की आशंकाओं से मुक्त जितने बच्चे जीवित रह जाते हैं, उनकी जीवन-स्थितियां कैसी हैं, इस पर अनुसंधान और अन्वेषण की हमारे यहां काफी जरूरत महसूस की जा रही है।

हैरानी की बात है कि एक मजबूत पारिवारिक ढांचे के बावजूद हमारे समाज में सबसे कम ध्यान बच्चों की तरफ दिया जाता है। आज भी परिवार में सबसे अधिक महत्व परिवार के प्रधान-पुरुष को मिलता है। उसकी सुख-सुविधा, खुशी-नाखुशी का हरदम खयाल रखा जाता है, लेकिन स्त्रियों और बच्चों की आशाओं और अपेक्षाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लाख हम कुछ शाश्वत सूत्र-वाक्यों के सहारे इस विषमता को ढक कर रखने की कोशिश करें, पर सचाई साफ नजर आती है। 'बच्चे घर का चिराग हैं,' 'बच्चे घर का मूल आधार हैं', 'बच्चे घर की रौनक और शान हैं,' ये और ऐसे सब सूत्र-वाक्य केवल आंख पर पट्टी की भूमिका अदा करते हैं, जब असलियत में हम देखते हैं कि बच्चों के विकास के प्रति सामान्यत: चेतना का घनघोर अभाव है। उनके व्यक्तित्व की संभावनाओं, सपनों और सामर्थ्य के संदर्भ में परिवार में एक लापरवाह रुख बना रहता है। एक औसत भारतीय परिवार अपने जीवन-संघर्षों में पिस चुकने के बाद इतना संकल्प और उत्साह जुटा ही नहीं पाता कि वह बच्चों का निर्माण बढ़िया ढंग से कर सके। घर में बच्चे नन्हे नौकर और नन्ही आया का जीवन बिताते हैं और इसके साथ-साथ वे थोड़ा-बहुत जो भी बन जायें उसी में सब्र करना सीखने के लिए मजबूर होते हैं।

कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं, जहां भौतिक साधनों का अभाव नहीं है। वहां बच्चों को अपनी न्यूनतम जरूरतों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन मार्ग-निर्देशन के अभाव में वे अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। जिन परिवारों में पति-पत्नी के आपसी संबंध सहज और स्नेहपूर्ण नहीं होते, वहां बच्चों की और भी दुर्दशा होती है। वहां बच्चों को मोहरा बना कर अहं की लड़ाई लड़ी जाती है। माता-पिता की परस्पर हार-जीत के दंगल में बच्चों का मंगल एक भूला हुआ सवाल बन जाता है। उन्हीं स्थितियों में ये खबरें नजर से गुजरती हैं कि किसी मां या बाप ने अपने समस्त बच्चों को मार कर स्वयं आत्मघात कर लिया। इस तरह की खबरों को पढ़ कर हर एक के मन में बच्चों के लिए करुणा उत्पन्न होती है, जिन्हें माता-पिता की कुंठाओं का शिकार बनना पड़ा। ◆

एक औसत भारतीय परिवार अपने जीवन-संघर्षों में पिस चुकने के बाद इतना संकल्प और उत्साह जुटा ही नहीं पाता कि वह बच्चों का र्माण बढ़िया ढंग से कर सके। घर में बच्चे नन्हे नौकर और नन्ही आया जीवन बिताते हैं और के साथ-साथ वे थोड़ा-बहुत जो भी बन जायें ी में सब्र करना सीखने लिए मजबूर होते हैं।

भारत की छाप

एक खोजपरक यात्रा

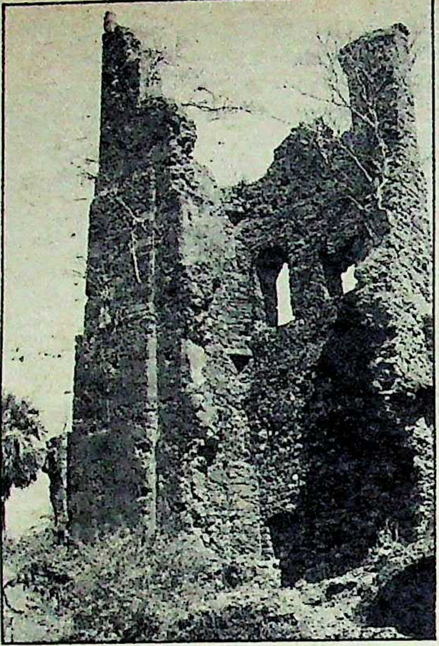

वसई में एक चर्च के खंडहर

सुहेला कपूर लिमये भरतनाट्यम की वेशभूषा में

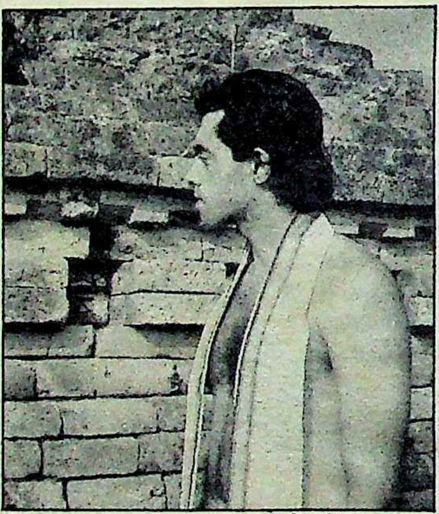

शिवकुमार सुब्रह्मण्यम नालंदा एपीसोड में

जिस अंगद सरीखे पांववाले टीवी सीरियल 'महाभारत' का समय खिसकाकर वहां 'उत्तर रामायण' के प्रदर्शन की सारी कोशिशें कर रामानंद सागर जैसे दिग्गज निर्माता हार गये थे, उस पांव को बिना किसी आहट के खिसकवाकर उसी टाइम स्लाट में नया सीरियल 'भारत की छाप' फिट करा लेना कोई मामूली बात नहीं। 'महाभारत' की जगह ५०-५० मिनट के १३ एपीसोडों वाले 'भारत की छाप' का प्रदर्शन एकबारगी क्यों शुरू हुआ, इसका जवाब सिर्फ मंडी हाउसवाले ही दे सकते हैं। इस सवाल का भी जवाब उन्हीं के पास होगा कि भारत के इतिहास से संबंधित 'भारत एक खोज' जब दिखलाया ही जा रहा था, तब 'भारत की छाप' को रविवार को उससे एक घंटे पहले प्रातः ९ बजे क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है?

एक असंतुष्ट सीरियल निर्माता ने 'माया' को बतलाया, "मंडी हाउस ने मान लिया है कि गजलगोई पर आधारित घटिया सीरियल 'गुफ्तगू' के साथ-साथ पंजाब की समस्या पर एकता के नाम पर तथाकथित सतही सीरियल तथा शनिवार को इसी समस्या पर उससे भी अधिक सतही टेली फिल्में, तथा हर रविवार को दर्शकों को इतिहास का पाठ पढ़ाने का जिम्मा 'दूरदर्शन' ने ओढ़ लिया है। यह सब कुछ नहीं, चुनावी तैयारी है, भगतजी की।" लेकिन 'भारत की छाप' की निर्देशिका छंदिता मुखर्जी ऐसा नहीं मानतीं।

श्याम बेनेगल की 'भारत एक खोज' को ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जा सकता है, 'भारत की छाप' वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रा कला की एक खोजपरक यात्रा है। पाषाणयुग आधुनिक काल तक हमारे देश में विज्ञान तकनीक की क्या स्थिति थी, इस क्षेत्र में कि तरक्की हुई और लोगों को प्राचीन काल तकनीकी ज्ञान किस हद तक था, इसकी त करने की छंदिता मुखर्जी ने कोशिश की है।

सफल कोशिश: जिस भारत की खोज सिर्फ ५२ एपीसीडों में कैद करना श्याम बेनेग लिए दुष्कर साबित हो रहा था, उसे छंदिता ने एपीसोडों में कर दिखाया है। उन्होंने समूचे काल को ११ एपीसोडों में विभाजित किया है। प्र एपीसोड प्रस्तावना तथा १३वां एपीसोड सम (रेट्रोस्पेक्ट तथा प्रास्पेक्ट) है। शेष ११ एपीस को पाषाण काल (३५०० ई०पू०), हड़प्पा सम (३५०० से १७२० ई०पू०), लौह युग (ई०पू० तक), भाषा युग (५०० ई०पू० से ई०), आयुर्वेद तथा अंतरिक्ष विज्ञान (३०० ई ७०० ई०), विज्ञान तथा मंदिर स्थापत्य (७० १२०० इ०), सिंथेसिस ऐंड ग्रोथ (१२००-१ ई०), स्टैगनेशन ऐंड चेंजिग वर्ल्ड (१६ १८०० ई०), उपनिवेशवाद एवं औद्योगिक क्र (१८००-१९०० ई०), स्वातंत्र्य संघर्ष साइंटिफिक कम्युनिटी (१९००-१९४७) स्वतंत्र भारत (१९४७ से अब तक) में विभा किया गया है।

सीरियल के लिए एक कथासूत्र का नि किया गया है जो अलग-अलग एपीसोडों को दूसरे से जोड़ता है। प्रो० निसीम (हेमू अधिका तथा कंप्यूटर वैज्ञानिक मैत्रेयी (वसुंधरा फ जो इस विषय पर फिल्म बनाना चाहते हैं, इसके वे पांच युवा संवाददाताओं शहनाज खान (सु कपूर लिमये), रघुनंदन (शिवकुमार सुब्रह्मण्य रंजन प्रधान (अनिरुद्ध लिमये) तथा अमृता प्र (ऊर्मि जयकर) तथा रामनाथन (जय ताताचार) की सहायता लेते हैं जो अलग-अ तथा कभी एक-दो सहयोगियों के साथ समूचे भ की वास्तविक लोकेशनों की विशद यात्रा कर उनकी फिल्म के लिए प्रमाण एवं दस्तावेज जुटा लोगों के साक्षात्कार लेते हैं, तो कभी-कभी उस के पात्रों के रूप में अभिनय भी करते हैं।

छंदिता से यह पूछे जाने पर कि आपने डाक्यूमेंटरी या नीरसता से बचाने के लिए किया है, तब वे कहती हैं, "मैंने संवादों की भाषा विशेष ध्यान दिया है, ताकि यह सीरियल दर्शक पल्ले आसानी से पड़ सके। इसके अलावा सिचुए को ध्यान में रखते हुए हास्य-व्यंग्य, प्रहसन, नृ संगीत भी शामिल किया है। कमेंट्री को उपदेश भाषणबाजी शैली से बचाने की भी कोशिश की है

—बंबई

बसेरा

मकान की समस्या का फिल्मी हल

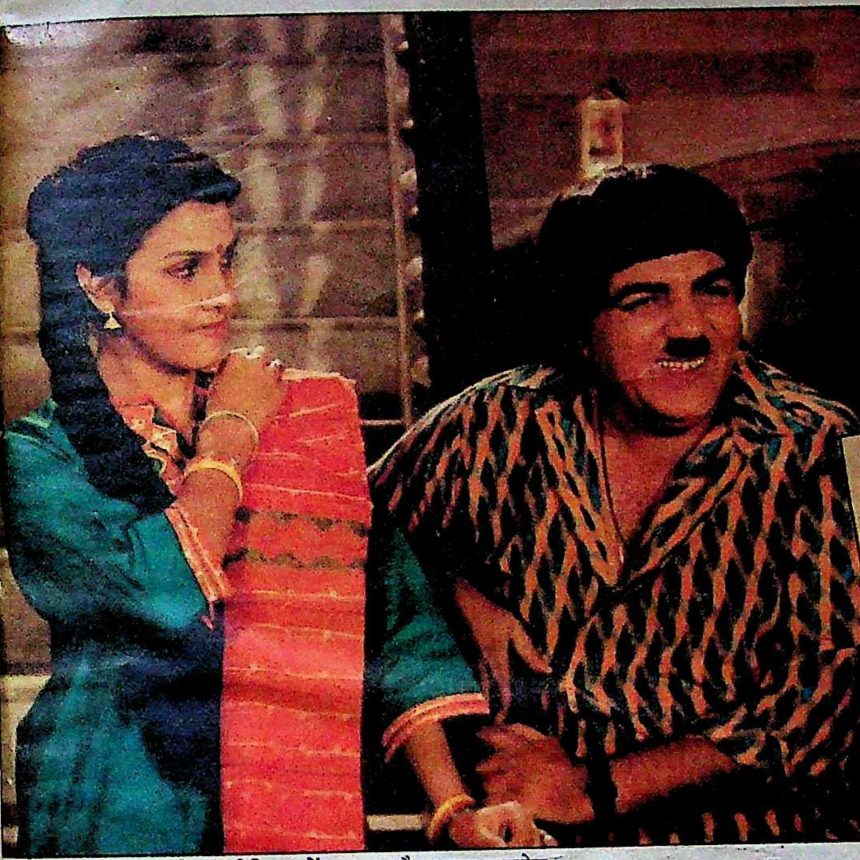

महमूद का कमाल : 'बसेरा' सीरियल में महमूद और चन्ना रूपारेल

नया विषय : माधुरी, महमूद और आलोका

'मेरी दिल्ली मेरी शान', 'जो यहां आया, यहीं का हो गया' जैसे पोस्टरों से पटी दिल्ली में सचाई यह है कि यहां नौकरी मिल सकती है, छोकरी (पत्नी) मिल सकती है, लेकिन मकान नहीं। मकान पाने के लिए अनेक उलटी-सीधी [illegible] पालन करना पड़ता है। तरह-तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ मकान मालिक तो ब्रह्मचर्य के प्राचीन भारतीय आदर्श को सर्वोपरि मान 'कुंआरों को मकान देने' की शर्त रखते हैं। महानगरों में मकान की इसी किल्लत का खट्टा-मीठा-चटपटा अनुभव दूरदर्शन पर शीघ्र प्रसारित होने वाले १३ कड़ियोंवाले सीरियल 'बसेरा' में दर्शकों को होगा। इसके चार कथांशों की शूटिंग गत दिनों दिल्ली में पूरी हुई।

कहानी : निर्माता अमरजीत और निर्देशक ज्योतिस्वरूप के 'बसेरा' की कहानी कुछ यों है। प्यारेलाल (महमूद) और बिंदु (चन्ना रूपारेल) पति-पत्नी हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है जिसमें केवल ये ही दो प्राणी रहते हैं। यह बंगला है लालाजी रावलपिंडीवाले का। प्यारेलाल उसका 'केयरटेकर' है। बंगले की देखभाल के लिए जितने पैसे चाहिए, उतने उसकी तनख्वाह में से नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में वह अपने दोस्तों से झूठ बोल-बोलकर पैसे उधार लेता है। बाद में उसकी नौकरी भी छूट जाती है। उसकी इस परेशानी में उसका मित्र अरविंदन रमन (अनंत महादेवन) उसे सलाह देता है कि क्यों न वह बंगले के पांच कमरों को किराये पर उठा देता। प्यारेलाल उसकी सलाह मान लेता है। उसकी यह शर्त थी कि वह कुंआरे व्यक्तियों को ही कमरे देगा। छह लोग किराये पर रहने के लिए आ जाते हैं। प्यारेलाल ने उनसे पगड़ी के रूप में मोटी रकम भी वसूल ली। किरायेदारों में तीन पुरुष और तीन स्त्रियां हैं। इनमें से दो ऐसे भी हैं जो वास्तव में पति-पत्नी हैं, लेकिन शर्त के कारण दोनों अपरिचित बनकर आते हैं। इनमें एक पत्रकार भी है। फिर शुरू होती है, दैनिक जीवन की सामान्य घटनाओं से पैदा होनेवाली नोकझोंक, तकरार और हास्य। किरायेदारों की रोजमर्रा जिंदगी में होने वाली विभिन्न घटनाएं प्यारेलाल और किरायेदारों की तू-तू मैं-मैं के टेढ़े-मेढ़े रास्तों से बिगड़ते-बनते संबंधों के उतार-चढ़ाव, प्यारेलाल का पुरुष किरायेदारों पर अपनी पत्नी से आंख लड़ाने के संदेहों का सिलसिला, रोज नये किरायेदारी कानून की रचना और किरायेदारों द्वारा कभी आंख बचाकर और कभी खुलेआम उल्लंघन, प्यारेलाल की रोक-टोक के बीच फलते-फूलते स्त्री-पुरुष प्रेम-संबंध, प्यारेलाल का अरविंदन रमन से उधार लेकर न देना और रमन द्वारा उधार वापस पाने की कोशिशें 'बसेरा' के हर एपीसोड को हंसी का फव्वारा बना देती हैं।

इसी बीच बंगले के असली मालिक लालाजी रावलपिंडीवाले रहने आ धमकते हैं। अब प्यारेलाल कैसे अपनी जान बचाता है, कैसे लालाजी आगबबूला होते हैं, किरायेदारों पर क्या गुजरती है, क्या-क्या बीतती है अविवाहित बनकर आये पति-पत्नी किरायेदारों पर, क्या होता है, इन तीन प्रेम-प्रसंगों का, रमन प्यारेलाल से उधार वसूल कर पाता है या नहीं और सबसे बढ़कर प्यारेलाल पर क्या गुजरती है? इन तमाम उलझे सवालों के जवाबों को बड़ी बेबाकी और हास्यपूर्ण ढंग से समेटा गया है, 'बसेरा' में। सीरियल में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से आये किरायेदारों के माध्यम से ज्वलंत सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर भी करारी चोट की गयी है।

सदाबहार हास्य अभिनेता महमूद पहली बार छोटे परदे पर केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पत्नी की भूमिका करनेवाली चन्ना रूपारेल 'चुनौती', 'महाभारत' और 'प्यार का बंधन' सीरियलों के माध्यम से चर्चित हैं। सीरियल के अन्य कलाकार हैं : 'ये जो है जिंदगी' की हास्यपूर्ण भूमिका से अपनी पहचान बनानेवाले राकेश बेदी, राम शेटी, माधुरी, आलोका मुखर्जी, प्रिया वाधवा और युवराज शर्मा।

—त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव

अनीता-सिद्धार्थ

एक दूजे के लिए

दूरदर्शन सीरियल 'क्विज टाइम' के जरिए सिद्धार्थ बसु ने करोड़ों दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी इस सफलता में उनकी पत्नी अनीता द्वारा परदे के पीछे किये गये गहन शोध कार्य का बहुत बड़ा हाथ है। लंदन के माहौल में पली कश्मीरी ब्राह्मण अनीता और मध्यंवर्गीय बंगाली परिवार के सिद्धार्थ बसु ने जीवन में तादात्म्य और व्यवसाय में ख्याति अर्जित करने के लिए अपने को किस रूप में ढाला है?

अनुकरणीय तालमेल : अनीता-सिद्धार्थ

"यदि पति-पत्नी में उचित तालमेल हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता का विमान उड़ान न भरे।" 'क्विज टाइम' के प्रस्तोता सिद्धार्थ बसु और उनकी कार्यक्रम समन्वयक व शोध-सहायिका पत्नी अनीता द्वारा अर्जित सफलता और प्रसिद्धि का यही राज है। अनीता से सिद्धार्थ की मुलाकात 'क्विज टाइम' के जरिए नहीं, बल्कि एक अंग्रेजी नाटक के कारण वर्षों पहले हुई थी। उसके बाद वे दोनों असली जिंदगी की प्रेम-कथा के नायक और नायिका बन गये।

यह प्रेम कहानी १४ साल पुरानी है। तब सिद्धार्थ दिल्ली के सेंट स्टीफन कालेज में अंग्रेजी साहित्य के स्नातकोत्तर छात्र और अनीता दिल्ली के मिरांडा हाउस में स्नातक की छात्रा थी। एक नाटक का निर्देशन करते समय सिद्धार्थ ने उस नाटक की नायिका अनीता को जब पहली बार देखा, तो देखते ही रह गये। सिद्धार्थ अनीता के बारे में विशेषणों की झड़ी लगाते हैं, तो लगाते ही चले जाते हैं, "वह जीवंत, सुंदर, सक्षम कलाकार थीं, बिलकुल मेरे सपनों की रानी जैसी...।" अनीता ने भी इस प्रतिभावान और गंभीर छविवाले युवक के अपने प्रति रुझान को अनदेखा नहीं किया। दोनों का प्रेम आठ वर्षों तक चला। एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार के होने के कारण सिद्धार्थ का विचार था कि जब तक वे लंदन में सुख-सुविधाओं में पली-बढ़ी अनीता को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक वे विवाह नहीं करेंगे। लेकिन अनीता का कहना है, "इसकी चिंता मुझे नहीं, सिद्धार्थ को ही अधिक थी।"

अतः सिद्धार्थ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मनोयोग से जुट गये। मंचीय अभिनय, निर्देशन और फिल्म निर्माण सिद्धार्थ के मनपसंद कार्यक्षेत्र थे। उन्हें आल इंडिया रेडियो में भी काम मिला और उन्होंने ताज होटल समूह के सांस्कृतिक मैनेजर के रूप में भी काम किया। अनीता भी पीछे नहीं थीं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और 'इंडिया टुडे' में संपादन और रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण लेने लगीं। अब दोनों कामकाज में लग गये थे। नतीजतन १९८३ में दोनों ने विवाह-बंधन में बंध जाने का फैसला कर लिया।

दोनों का अंतरजातीय प्रेम-विवाह था। लेकिन इससे कोई अनावश्यक तूफान नहीं मचा। सिद्धार्थ के माता-पिता ने सहर्ष इस संबंध को स्वीकार कर लिया, जबकि अनीता के माता-पिता कश्मीरी ब्राह्मण परिवार होने के कारण अपनी जाति के बाहर कन्या का विवाह होने से थोड़े चिंतित अवश्य थे। अनीता बताती हैं, "अब सब कुछ ठीकठाक है। मेरे माता-पिता ने सिद्धार्थ को उसी तरह स्वीकार कर लिया है, जिस तरह मुझे।" यह कहते हुए अनीता की आंखों में शरारत नाच उठती है।

बंगाली परिवार में रच-बस जाने में नव वधू को कोई परेशानी नहीं हुई। अनीता का कहना है, "मेरी ससुरालवाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे पारंपरिक बंगाली वधू जैसा आचरण करने की अपेक्षा नहीं की। मैं साड़ी नहीं पहनती और उन्होंने इस स्थिति को सहज ही स्वीकार कर लिया है।"

घरेलू मोर्चे पर भी अनीता कम भाग्य नहीं हैं, लेकिन 'क्विज टाइम' की बेहद सफल और उसके कारण एक विशेष लोकछवि बन जा उन्हें अपनी जीवन-शैली में आवश्यक परिवर्तन क पड़े। अनीता कहती हैं, "हमें वह जताना पड़ता, हम वास्तव में नहीं थे और यह एक ऐसी बात जिसे हम दोनों नापसंद करते हैं।" सिद्धार्थ अ अनीता बड़े नामी-गिरामी लोगों के बीच अनावश्य उठने-बैठने के बजाय खाली समय में अपने घनि मित्रों के साथ अपने घर में समय गुजारना क बेहतर समझते हैं। ऐसा करना स्वाभाविक भी है अपने इन घनिष्ठ मित्रों के सहयोग से ही वे एक टी का निर्माण कर सके और इन्हीं के दम पर उन्हों १९८८ में 'सीनेर्जी कम्युनिकेशंस' नाम से एक न प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना कर डाली।

सिद्धार्थ बताते हैं, "हम मूलं रूप से फि और वीडियो-निर्माण, दूरदर्शन कार्यक्रम औ पुस्तकों के डिजाइन करने के व्यवसाय में लगे हैं।" इस प्रोडक्शन कंपनी की सफलता का सब बड़ा प्रमाण 'क्विज टाइम' और 'सार्क क्वि स्पेक्ट्रम' सीरियलों की बेहद लोकप्रियता है। इ दिनों वे न केवल २३ खंडों के दूरदर्शन सीरिय 'इंडिया क्विज' के निर्माण में जुटे हैं, बल्कि इन्हों इंडियन कौंसिल फार कल्चरल रिलेशन के लि 'नृत्य' को प्रोत्साहन देने के निमित्त पांच फिल्मों क निर्माण पूरा कर लिया है तथा एक पुस्त 'इन्क्विजीटिव इज द इंप्रिंट' के नाम से लिख डाल है, जिसे कलकत्ता की 'सीगल बुक्स' प्रकाशन संस्थ

ाशित कर रही है। अभी यह पुस्तक छपी नहीं है, किन छपने के पूर्व ही इस पुस्तक की एक हजार तियों से अधिक के अग्रिम बिक्री-आदेश प्रकाशक प्राप्त हो चुके हैं।

अनीता गर्व के साथ कहती हैं, “इसमें कोई क नहीं है कि इस सारी मेहनत की प्रेरणा सिद्धार्थ । सिर्फ ३६ वर्ष की वय में इतनी सफलता प्राप्त र लेना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।” लेकिन द्धार्थ का कहना है, “मुझे तो एक लंबा सफर तय रना है।” बहरहाल, सिद्धार्थ अपनी सफलता की हानी में अपनी पत्नी की अहम भूमिका को ीकार करने में कोताही नहीं करते। उनका कहना “वह मेरी ताकत है और हर तरह से मेरी हयोगी है, लेकिन कभी-कभी फिजूल की बातों में द परेशान होकर तथा मुझे परेशान करके वह खुद पनी महत्ता को कम करने की कोशिश करती है।” रअसल, लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ सिद्धार्थ ी महिला-प्रशंसकों की संख्या भी बढ़ रही है जो नीता को नागवार लग सकती है। अपनी बात का ुलासा करते हुए सिद्धार्थ बताते हैं, “मेरी पत्नी मुझ र एकछत्र अधिकार रखना चाहती है और कभी-भार बिना यह समझे कि मैं बड़ा स्थिर हूं और बंधों में अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता कार परेशान हो जाती है।” सिद्धार्थ के इस क्तव्य से अनीता खिल-खिलाकर हंस पडती हैं, ानो पति की पत्नी-भक्ति की पुष्टि कर रही हों। सरी ओर, सिद्धार्थ भी इस बात को नजरअंदाज हीं कर पाते कि उनकी पत्नी पर किसी मर्द की जर पड़े, लेकिन वे कहते हैं, “मैं इसकी परवाह नहीं रता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी की निष्ठा में कोई देह नहीं है। शुरू-शुरू में मैं अवश्य ईर्ष्यालु और सुरक्षित महसूस करने लगता था, लेकिन अब मैं ह मानने का अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया हूं कि री पत्नी खूबसूरत है और मुझे बेहद प्यार करती है।” सिद्धार्थ की इस घोषणा से उनकी पत्नी अनीता के चेहरे पर आश्वस्ति के भाव उभर आते हैं और वे ऐसे देखने लगती हैं, मानो कह रही हों कि उनकी भी अपने पति के प्रति वैसी ही धारणा है।

एक-दूसरे के पूरक: अनीता-सिद्धार्थ

हां, अनीता भी अन्य पत्नियों के समान यह शिकायत करने में नहीं चूकतीं कि उनके पति घरेलू कामों में मन नहीं लगाते। अनीता कहती हैं, “अपने बच्चों के भविष्य और अन्य घरेलू कामों के संबंध में उसका मुझसे अधिक दायित्व है।” लेकिन सिद्धार्थ की इस बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता कि वे प्रतिदिन सायं साढ़े छह बजे के बाद का वक्त घर पर ही गुजारते हैं। अनीता जोर देती हैं, “केवल घर पर रहना ही पर्याप्त नहीं है, उसे घर में और रुचि लेनी चाहिए।” सिद्धार्थ थोड़े अनमने ढंग से स्वीकार करते हैं कि उन्हें इस संबंध में कुछ-न-कुछ करना ही पड़ेगा। वे स्वीकार करते हैं, “मैं इन सब कामों को अच्छी तरह नहीं कर सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी पत्नी ठीक कह रही है।”

सिद्धार्थ और अनीता पूरी कोशिश करते हैं कि घर में किसी तरह का तनाव न हो। वे सामान्यतः अपने मिजाज को ठंडा रखते हैं। अनीता कहती हैं, “जब मुझे गुस्सा आता है, तो मैं कई दिनों तक उससे बात नहीं करती।” लेकिन वे यह भी स्वीकार करती हैं, “सिद्धार्थ का ठंडा मिजाज संतुलन कायम करने और मरहम लगाने का काम करता है और मैं तत्काल शांत हो जाती हूं।” सिद्धार्थ भी सुलझे दिलो-दिमाग के हैं और अपनी पत्नी की किसी विपरीत बात को गांठ बांधकर नहीं रखते। उनका कहना है, “वह जैसी है, मुझे स्वीकार्य है और वास्तव में मुझे उस पर बेहद गर्व है।” बहरहाल घर में कभी-कभार होनेवाले छोटे-मोटे झगड़ों से यह जोड़ा अप्रभावित रहता है, क्योंकि अनेक कार्य ऐसे हैं, जिनमें दोनों की समान रुचियां हैं। सिद्धार्थ का कहना है, “हमने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं।”

अंग्रेजी साहित्य, नाटक और फिल्म निर्माण ऐसे विषय हैं, जिनमें दोनों की समान रुचियां हैं और दोनों इन्हीं विषयों पर बिना झगड़े विचार-विमर्श और वाद-विवाद में घंटों व्यस्त रहते हैं। दोनों का कहना है, “हम एक दूसरे की पसंद को नजरअंदाज नहीं करते।” यदि अनीता फिल्म आदि के निर्माण के संबंध में सिद्धार्थ के खयालों का सम्मान करती हैं, तो सिद्धार्थ भी अनीता की अभिरुचि का सम्मान करते हैं। मसलन, सिद्धार्थ चाहते हैं कि अनीता स्वतंत्र रूप से अपने कार्यक्षेत्र का निर्माण करे और उसमें महारत हासिल करे, जिससे अपनी प्रोडक्शन कंपनी में उसका पृथक अस्तित्व स्थापित हो। सिद्धार्थ खुलासा करते हैं, “पुत्र आदित्य के जन्म के बाद अनीता को पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अपने इस निर्णय पर उसे कभी पश्चाताप हो। इसी कारण मैं चाहता हूं कि वह हमारी कंपनी में अपनी प्रतिभा और कौशल के बल पर स्वयं विकसित हो। अपने निर्माण-कार्यों के लिए आवश्यक संदर्भ जुटाने में उसके पत्रकारिता क्षेत्र के कौशल और अनुभव का उपयोग करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं।” अनीता का कहना है, “खुद वह भी अपनी ‘क्विज मास्टर’ की छवि से आजिज आ चुका है। वह मूल रूप में एक अभिनेता है, जिसने अंग्रेजी के अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, लेकिन बहुत कम लोग उसके इस रूप से परिचित हैं। इसका कारण संभवतः यही है कि वे नाटक हिंदी में नहीं थे।

दरअसल, सिद्धार्थ ने एक हिंदी सीरियल ‘पुरवाई’ में अपनी प्रतिभा को आजमाया था, लेकिन सिद्धार्थ के अनुसार वे बुरी तरह असफल साबित हुए। सिद्धार्थ का कहना है कि हिंदी वह भाषा नहीं है जिसमें वे सोच सकें और अभिनय को जीवंत बनाने के लिए बेहद जरूरी है कि पात्र नाटक की भाषा में ही सोचे।”

यह दंपती अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की असीम ऊंचाइयों का स्पर्श करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पेशे के उतार-चढ़ाव से वे न तो हताश होते हैं और न ही अपनी निजी जिंदगी को प्रभावित होने देते हैं। यह उनकी अटल लगन और कार्य के प्रति असीम निष्ठा का परिणाम है कि उनकी जिंदगी का सफर सहज और सुखपूर्ण है। सिद्धार्थ का कहना है, “संबंधों के प्रति हमेशा चिंतित बने रहने की जरूरत नहीं होती। ड्राइविंग सीख लेने के बाद तो हाथ-पैर आदतन कार्य करने लगते हैं और हर बार इस बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहती कि गाड़ी का गेयर या क्लच कहां है? इसी तरह १४ वर्षों के संबंधों के बाद भी यदि यह चिंता रहे कि कहीं हमारे संबंध टूट न जायें, तो सब बातें अर्थहीन हो जायेंगी?” वास्तव में सिद्धार्थ और अनीता ऐसे सौभाग्यशाली और व्यस्त पति-पत्नी हैं कि मतभेद के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है।

मा शास्त्री

ा: सुनील सक्सेना

111153.

खुशबू का जलवा

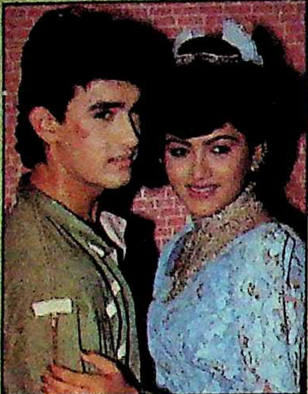
खुशबू और आमीर खान
छाया: आरवी तिवारी

बंबइया फिल्मवालों के रवैये से नाराज हो खुशबू ने कसम खा ली थी कि जब तक यहां के लोग उसे बुलाने के लिए दस चक्कर नहीं लगायेंगे, तब तक वह बंबई का रुख नहीं करेगी। ईश्वर ने उसके मन की कराह सुनी और रातोरात उसे दक्षिण की फिल्मों की 'श्रीदेवी' बना दिया। स्टार बन गयी खुशबू की सफलता की खुशबू जब बंबई पहुंची, तो नयी पीढ़ी की नायिकाओं के नखरों से परेशान बंबइया फिल्म निर्माताओं ने दक्षिण के चक्कर लगाने शुरू कर दिये।

ईश्वर ने रूठी खुशबू की तमन्ना पूरी की और उसकी बांछें बंबइया आफरों को पाकर खिल उठीं। सोनम तथा एकता के नखरों से परेशान निर्माताओं ने उनकी जगह खुशबू को लेना शुरू कर दिया और खुशबू ने अपनी सफलता का जो पहला ठप्पा दर्जनों लोगों की मौजूदगी में लगाया, उसे सबसे पहले आमीर खान ने महसूस किया और उस ठप्पे की गर्माहट ने आमीर की दूसरी नायिक़ाओं सहित उसकी एक अदद बीवी को भी हलकान कर दिया, तो इसमें खुशबू का क्या दोष? आखिर उसने अपनी पहली ही फिल्म में एक लंबा-सा चुंबन दृश्य देकर एक छोटा-मोटा कीर्तिमान जो बना लिया था।

जैकी का जैकपाट

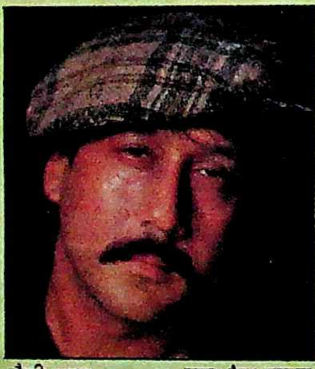
जैकी श्राफ छाया: तैयब बादशाह

अचानक हाथ लग गयी सफलता के जैकपाट के लिए जैकी किसे श्रेय दें—देव आनंद ('सच - का बोलबाला'), महेश भट्ट ('काश') या सुभाष घई ('राम-लखन') को? यह सोचकर जैकी अजीब-सी दुविधा में फंस गये हैं, क्योंकि अलग-अलग बयानों में वे तीनों को अपना 'फ्रेंड, फिलासफर और गाइड' करार दे चुके हैं। देव आनंद ने उन्हें सबसे पहले 'स्वामी दादा' में मौका दिया, सुभाष घई ने उन्हें सबसे पहले नायक ('हीरो') बनाया और महेश भट्ट ने उन्हें 'काश' में डिंपल कपाड़िया के पति की भूमिका देकर इस तरह का रोल निभाने की उनकी लंबी मुराद पूरी कर दी।

सुभाष घई जब राम-लखन बना रहे थे, तो फिल्म के राम और लखन (जैकी एवं अनिल कपूर)—दोनों एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देखा करते थे कि उनमें से कोई एक-दूसरे पर हावी न हो जाये। 'राम-लखन' ने लखन (अनिल) का भाग्य तो चमकाया ही, राम (जैकी) को भी असफलता के बनदास से उबार लिया। लेकिन अपनी पुनः वापसी का सेहरा जैकी सुभाष घई को नहीं, देव आनंद को देते हैं, जिन्होंने उन्हें 'सच का बोलबाला' में पावरफुल रोल दिया था और बकौल जैकी, उन्होंने यह साबित कर दिया था कि उनमें स्टार-टेलेंट अभी भी मौजूद है। देव आनंद को 'चुका हुआ' माननेवाले घई को तब जरूर धक्का पहुंचा, जब उनके उस पटु शिष्य ने कहा, "देव साब आज भी बड़े-बड़ों को पानी पिला सकते हैं।"

अब बेचारे जैकी क्या करें जो सुभाष घई ने खुद को भी 'बड़ा' मान लिया!

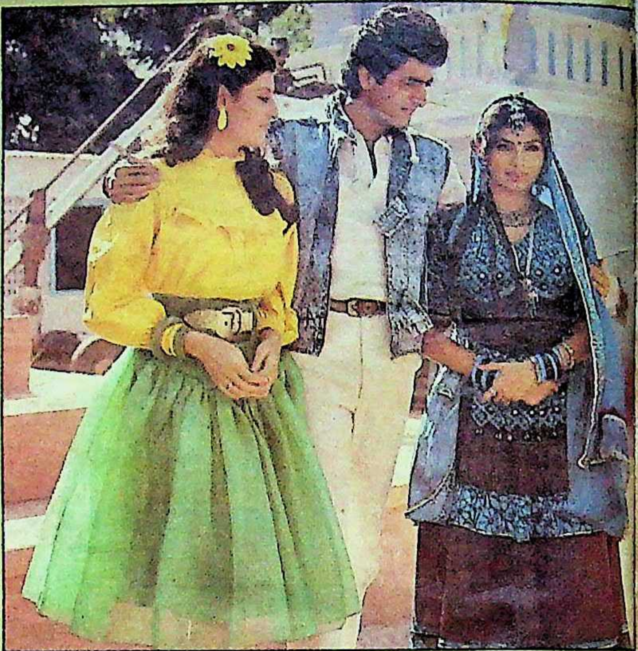
किमी कातकर, कुणाल गोस्वामी और संगीता बिजलानी छाया: डीआर

पूत के रंग

पापा मनोज कुमार सारी जिंदगी फिल्मों के रोमानी दृश्यों में नायिका को आलिंगनबद्ध करने से इसलिए कतराते रहे कि कहीं उनकी 'भारत-इमेज' को धक्का न पहुंचे। लेकिन उनके सुपुत्र कुणाल गोस्वामी केवल अंतरंग दृश्यों से ही संतुष्ट नहीं होते, निर्देशक को थोड़ा और 'रियलिस्टिक' होने की भी सलाह देते हैं। पापा मनोज का उदाहरण देने
नहले-पर-दहला इस अंदाज में मा
हैं जैसे आलिंगन तथा चुंबन दृश्यो
परहेज कर उनके पापा ने 'बिर
जनम गंवायो' हो—"अब जो क
पापा ने नहीं किया, क्या जरूरी है
उसे मैं भी न करूं? वे लोग परदे
कुछ तथा परदे के बाहर कुछ
जिंदगी जीते रहे—मैं तो
जिंदगी एक-सी ही जीना चा
हूं...।"

सोनम-चंकी की दोस्ती

सोनम और चंकी पांडेय छाया: महेश जाली

'चट दोस्ती पट कुट्टी' में माहिर माने जानेवाले चंकी पांडे तथा सोनम अचानक एक बड़ी मामूली-सी बात पर एक दूसरे से ऐसे खफा हुए कि पूरे तीन महीने तक एक दूसरे से नहीं बोले। सेट पर जाते, सीन के मुताबिक अंतरंग और चुंबन दृश्य देते, फिर कैमरे के सामने से हटते ही एक दूसरे से बेगाने बन जाते, दूसरे से हंस-हंसकर बेलाग बातें करते
एक-दूसरे के दिल पर छुरी चला
कुट्टी सिर्फ इस बात पर हुई थी
एकता के लिए साफ्ट ड्रिंक का
गिलास स्पाट ब्वाय ला रहा था,
चंकी ने बीच में ही लपककर
एकता को थमा दिया, जिसे सोन
फूटी आंखों नहीं सुहाती।

अब जैसे दोनों में कुट्टी हुई
उसी तरह दोनों की दोस्ती भी
गयी। इत्तिफाक से दोनों जुहू
जागिंग के लिए अलस्सुबह गये,
नारियल-पानी पीने के लिए एक
दूकान पर रुके। दूकानदार ने 'ले
फर्स्ट' परंपरा का पालन करते
नारियल-पानी सोनम की ओर ब
दिया। पता नहीं सोनम को क्या सू
कि उसने वह नारियल-पानी
की तरफ बढ़ा दिया।

—अखबारी

श्री वीरेन्द्रनाथ घोष द्वारा मित्र प्रकाशन प्रा०लि० के लिए प्रकाशित तथा माया प्रेस प्रा०लि०, इलाहाबाद—३ में मुद्रित। दिल्ली कार्यालय—१०५ रोहित हाउस
३ टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—११०००१।

Checked
1999-2000

111153